Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Gurukul Kangri Collection, Haridwar

INDIA T[illegible]

1988

Jan-Jun

G. K. V.
Hardwar

Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

a8631

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

078631

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

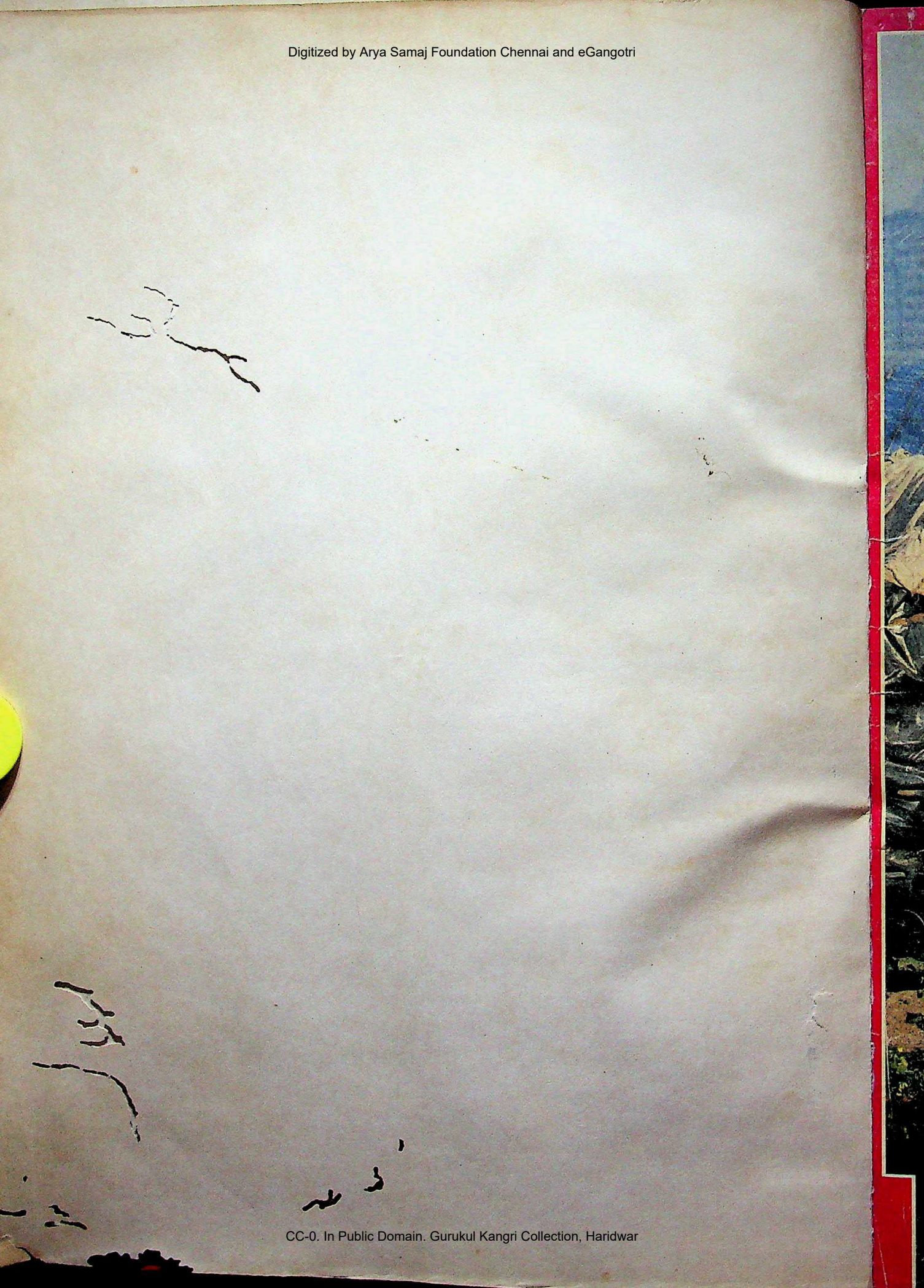

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

31 जनवरी 1988 5 रुपए

इंडिया टुडे

संपूर्ण समाचार पत्रिका

जीव: निर्जन टापू पर निश्चित
मध्यप्रदेश: परंपरा की व्यथाकथा
श्रीलंका: जल्दबाजी का महंगा खामियाजा

JAN-JUN 32
1988
078631

नरक बनते नगर

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अंतर्राष्ट्रीय
सॉफ्ट-स्क्वीज़ ट्यूब.

३ कमाल वाला टूथपेस्ट
त्यों हमने भी अपनाया"

मानिए या ना मानिए, पर मैंने तो सचमुच अपना टूथपेस्ट बदल डाला है! अब
ने अपनाया है **लौंग, फ्लोराइड** और **मिन्ट** के ३ कमाल वाला प्रूडेन्ट. है मेल
ना अच्छा, इनों दांतों का साथी सबसे सच्चा!
नुराधा ने एक और खूबी पायी – प्रूडेन्ट की सॉफ्ट-स्क्वीज़ ट्यूब! सदा रहे
फ-सुथरी. ऐसी खूबी और किसी टूथपेस्ट में कहां है!"

न! दांतों की देखभाल के लिए रंगीन पुस्तिका. सीमित संख्या में.
खिए : पारले प्रॉडक्ट्स प्रा. लि., नेर्लोन हाउस, २५४-बी, डॉ. ए.बी. रोड, बम्बई ४०० ०२५.

ूडेन्ट में हैं कमाल ३, दांतों के लिए बेहतरीन

पारले

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

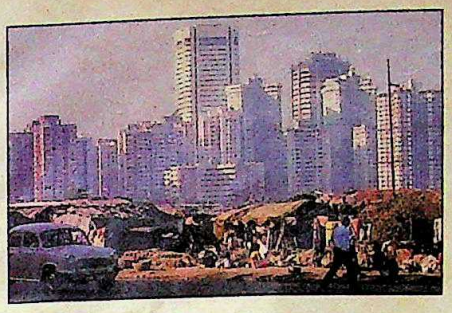

खस्ताहाल जिंदगी, बदहाल नगर

आबादी तेजी से बढ़ने के कारण शहरों का फैलाव बेकाबू होता जा रहा है. ऐसे में, जबकि झुग्गी बस्तियों, पानी, यातायात और प्रदूषण की समस्याएं शैतान की आंत की तरह बढ़ रही हों इस पर गंभीरता से गौर करना जरूरी हो गया है कि आखिर महानगर जा कहां रहे हैं?

आवरण कथा 70

निर्जन टापू पर निश्चित पड़ाव

जब राजीव गांधी अपने परिवार और मित्रों के साथ बंगारम में छुट्टियां मना रहे थे, तो समाचार माध्यमों का ध्यान लक्षद्वीप समूह के इस छोटे से टापू पर केंद्रित हो गया था. पर अखबारी आलोचना के बावजूद प्रधानमंत्री की टोली की छुट्टियां मजे में कटीं. खास रिपोर्ट.

आजकल 14

बेमिसाल अदालती फैसला

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री एन.टी. रामराव के खिलाफ पद का दुरुपयोग करने के प्रथम दृष्ट्या सबूत पा लिए हैं. इस फैसले और फैसला देने के अजीबोगरीब ढंग से आंध्र प्रदेश में ऐसी राजनैतिक आंधी चल पड़ी है कि मुख्यमंत्री रामराव का आसन डोलने लगा है.

आजकल 24

जल्दबाजी का महंगा खामियाजा

श्रीलंका में तमिल मुक्ति चीतों के विरुद्ध भारतीय सेना की कार्रवाई आजादी के बाद भारतीय सेना की सबसे लंबी लड़ाई में तब्दील हो गई है. इस लड़ाई का मौके पर जाकर लिखा गया ब्यौरा और इस अद्भुत लड़ाई से सेना को मिले सबक की समीक्षा.

खास रपट 42

पुराने शहर का नया रंगरूप

पिछले कुछ सालों में रूढ़िवाद का गढ़ माने जानेवाले शहर मद्रास में आधारभूत परिवर्तन आए हैं. अब यह एक प्रगतिशील शहर है. पर रूढ़िवाद और आधुनिकता के द्वंद्व के कारण इस पुराने शहर में कई तनाव और समस्याएं भी खड़ी हो गई हैं.

विशेष लेख 48

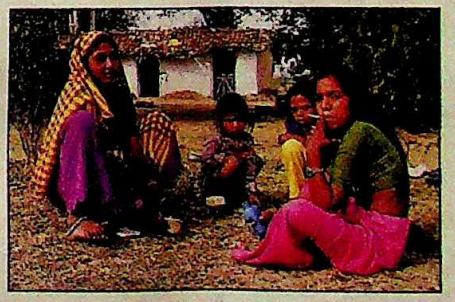

परंपरा की व्यथाकथा

मध्य प्रदेश के बांछड़ा समुदाय में घर की सबसे बड़ी बेटी को वेश्यावृत्ति करके घर चलाने में मदद करने के लिए विवश किया जाता है. सरकार ने इस परंपरागत कुप्रथा के खात्मे के लिए कभी पूरे मन से कोशिशें नहीं की. नतीजतन बांछड़ा जहां के तहां ही रह गए हैं.

रहन-सहन 80

कसौटी.....9
तेवर.....10
राजरंग.....11
हिंदोस्तां हमारा.....12
बीता पखवाड़ा.....13
आजकल
प्रधानमंत्री की छुट्टियां:
निर्जन टापू पर निश्चित पड़ाव.....14
गोपी अरोड़ा: चौकड़ी से बाहर.....17
हरियाणा: इस्तीफों की राजनीति.....18
कर्नाटक: दरक रहा मजबूत किला.....20
आंध्र प्रदेश: बेमिसाल अदालती फैसला....24
फेयरफैक्स: शांत जल में फिर हलचल.....28
उत्तर प्रदेश: दिल जीतने की लड़ाई.....30
विपक्ष: विकल्प बनने के मंसूबे.....32
तमिलनाडु: जानकी की अग्निपरीक्षा.....34
महाराष्ट्र: अनुकरणीय निर्णय.....37
दिल्ली: मैदान छोड़ दिया.....38
बिहार: गद्दी बचाने की तिकड़म.....39
मेघालय: सियासी झटके.....40
आखिरी बात.....41
खास रपट
ऑपरेशन पवन:
जल्दबाजी का महंगा खामियाजा.....42
विशेष लेख
मद्रास: पुराने शहर का नया रंगरूप.....48
राज्य-दर्पण.....54
व्यापार-चक्र.....59
कारोबार
तेजरफ्तार रेलगाड़ियां:.....61
विदेशी विमान सेवाएं: बंद होती दुकानें....62
प्रत्यक्ष कर विधेयक:
बदलाव, या बदले का भाव.....63
प्रचारक ग्रंथावली: चमत्कारी प्रयास.....66
निर्यात: संभावनाएं असीम.....67
शेयर बाजार: दुलकी चाल.....68
आवरण कथा
शहरीकरण: खस्ता जिंदगी, बदहाल नगर.70
रहन-सहन
मध्य प्रदेश: परंपरा की व्यथा कथा.....80
कला
परमवीर: विदेश ने कराई पहचान.....84
छायालेख
युद्धकलाएं: लहराते जिस्मों की जांबाजी....86
किताबें.....90
सिनेमा
इंसाफ की पुकार: वही बासी लटके.....92
शहंशाह: परदे पर आने में हिचक.....94
धरोहर
तंजावुर: एक अद्भुत उपक्रम.....96
स्वास्थ्य
केरल: आधुनिक इलाज की पहल.....97
धर्म
महेश योगी: अधर में लटका अध्यात्म.....99
चर्चित चेहरे.....104

आवरण: रघुराय

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

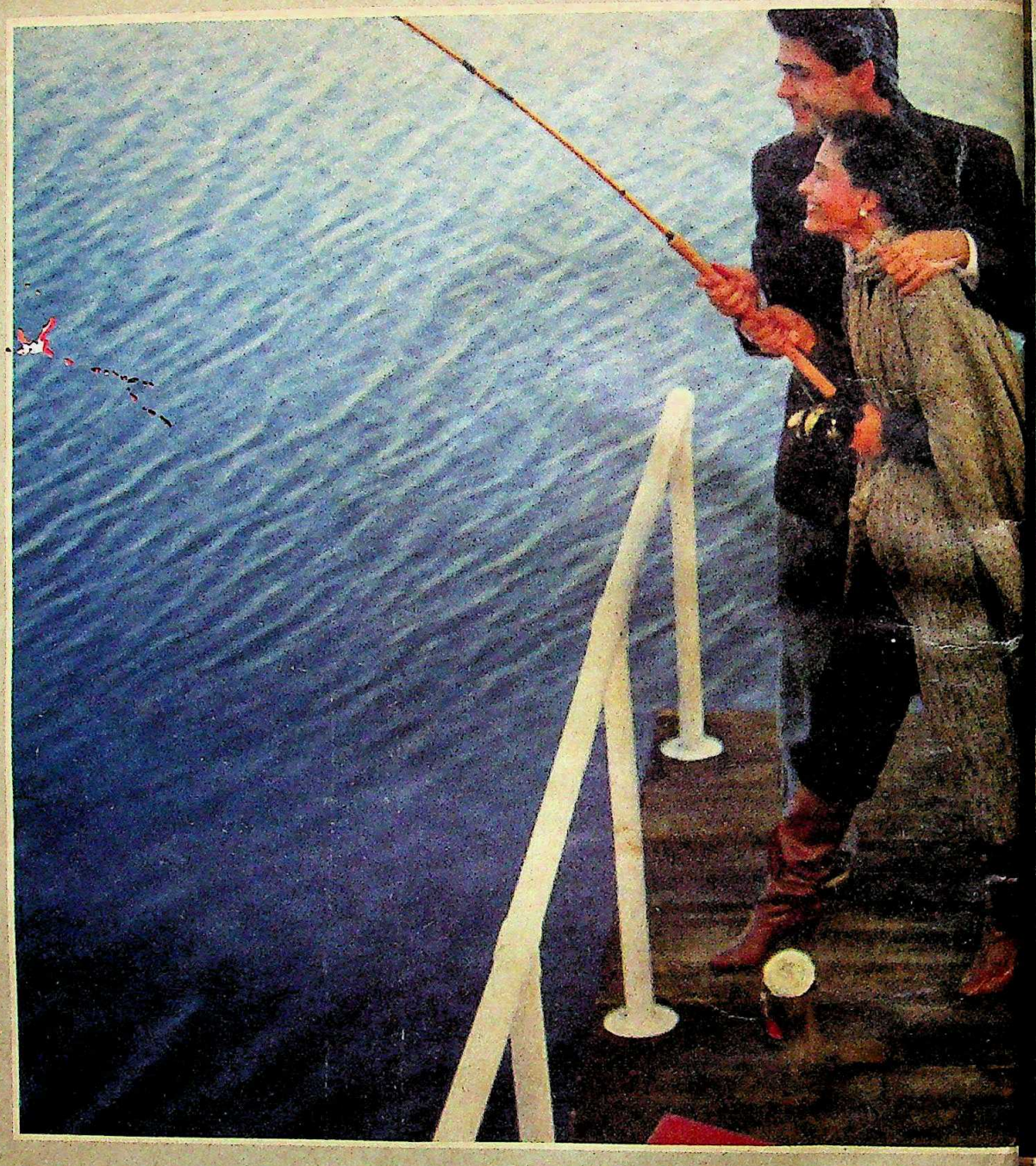

"मछली थोड़े ही है, वो तो यूं ही..." मैंने कहा
मानना ही पड़ेगा।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'कौवे बोली' मैं जो कहती हूँ, मछली ही है'...

ट्वीड सूटिंग

जीवन के विजयी क्षणों में **रैमण्ड**

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"धोखा खाना भला कौन पसंद करेगा"

दुनिया में सबसे बुरी अनुभूति शायद बेवकूफ बनना ही है। खास कर उस समय जब आप किसी वस्तु पर अपना विश्वास प्रकट कर चुके हों और वह बाद में बेकार साबित हो जाए। वाकई यह एक शर्मनाक स्थिति होती है। जब आप पूरे परिवार के लिए ख़ास चीज खरीदते हैं उस समय हर कोई उत्सुक होता है क्योंकि यह एक पारिवारिक खुशी का मौका होता है। और आप भी अपने आपको पुरस्कृत महसूस करते हैं जब आप देखते हैं कि आपकी मेहनत रंग लाई है।

और फिर एक हफ़्ते या एक महीने के बाद आपको पता चलता है कि आप गलती कर बैठे हैं। आप सभी के चेहरों पर मायूसी देखते हैं क्योंकि आप एक गलत वस्तु खरीद बैठे हैं और अब तो काफी देर भी हो चुकी है। आप उस वस्तु को खरीद कर फंस गए सा महसूस करते हैं और जब भी आप उस वस्तु की ओर देखते हैं आप अपने आपको बेवकूफ सा समझते हैं।

क्यों न टीवी निर्माता, टीवी खरीदने में किसी भी प्रकार के जोखिम को रहने ही न दें।

आपकी उलझन सुलझाए तमाम, जी हां, सिर्फ हॉटलाइन है नाम।

पेश है... दो साल की बेमिसाल गारण्टी।

EUROPA BY HOTLINE

FBL-HIN/1

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इंडिया टुडे
संपूर्ण समाचार पत्रिका

वर्ष: 2, अंक:6, 16-31 जनवरी 1988

प्रधान संपादक: अरुण पुरी

वरिष्ठ संपादक: प्रभु चावला

लिविंग मीडिया इंडिया प्रा. लि., एफ-14, कंपिटेंट हाउस, कनाट प्लेस, नई दिल्ली के लिए अरुण पुरी द्वारा संपादित और प्रकाशित तथा थॉमसन प्रेस इंडिया लि. फरीदाबाद , हरियाणा में मुद्रित.

संपादकीय कार्यालय:
लिविंग मीडिया इंडिया प्रा. लि., एफ-14/15, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001. फोन: 331 5801-4, टेलेक्स: 31-61245 INTO IN, तार: लिवमीडिया नई दिल्ली.

मुख्य सर्कुलेशन कार्यालय:
इंडिया टुडे सर्कुलेशन मैनेजर, एफ-14, कंपिटेंट हाउस, कनाट प्लेस, मिडल सर्कल, नई दिल्ली-110001. फोन: 3313076-8, टेलेक्स: 31-62634 INTO IN, तार: सर्कुलेट, नई दिल्ली.

मुख्य विज्ञापन कार्यालय:
28 ए और बी, जॉली मेकर चैंबर-2, नरीमन पाइंट, बंबई-400021. फोन: 2026152, 2029326, 2029435, टेलेक्स: 11-5373 THOM IN, तार: लिवमीडिया बंबई.

क्षेत्रीय विज्ञापन कार्यालय:
के-9, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001, फोन: 352378, 323576, 351273, 351323; टेलेक्स: 31-62124 THOM IN, तार: लिवमीडिया, नई दिल्ली ; फागुन चैंबर्स, 26 कमांडर-इन-चीफ रोड, मद्रास-600105. फोन: 477188, 477770, टेलेक्स: 041-6177 INTO IN, तार: लिवमीडिया, मद्रास ; 74/1, सेंट मार्क्स रोड, बंगलूर-560001. फोन: 568448, 579037, 579089, टेलेक्स: 0845-2217 INTO IN, तार: लिवमीडिया, बंगलूर ; 12-सी, एवरेस्ट 46-सी, चौरंगी रोड, कलकत्ता-700016 फोन: 445398, 447726, टेलेक्स: 021-3138 INTO IN, तार: लिवइन-मीडिया, कलकत्ता.

कॉपीराइट 1984 लिविंग मीडिया इंडिया प्रा. लि. विश्व भर में सर्वाधिकार सुरक्षित. किसी भी रूप में सामग्री की नकल प्रतिबंधित. इंडिया टुडे अनिमंत्रित प्रकाशन सामग्री को लौटाने की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता.

नेपाल में 6 रुपए

पतझड़ में बीता वर्ष

आवरण कथा 'विडंबनाओं का वर्ष' (15 जनवरी) में हर क्षेत्र के दो विपरीत छोरों का जो आकलन किया गया है उसके मूल में राजीव की सिद्धांतहीन और अहं से भरपूर राजनीति ही है. मां की मृत्यु के बाद मिले प्रचंड बहुमत से वे भारत की सभी मान्यताओं से खिलवाड़ कर रहे हैं.

—राधेश्याम गोयल, मेरठ (उ. प्र.)

■ सन '87 को 'विडंबनाओं का वर्ष' विशेषण से प्रस्तुत कर आपने वास्तव में सही विवेचन किया है. नेताओं, खिलाड़ियों, अभिनेताओं, सैनिकों, व्यापारियों से लेकर एक सामान्य आदमी तक के लिए बीता वर्ष बहुत खराब रहा. अनेक दुर्घटनाओं और अवसादों से भरे गुजरे साल की पुनरावृत्ति इस रूप में कभी न हो, यही कामना है.

—अजय माथुर, सुजानगढ़ (राज.)

■ विडंबनाओं के वर्ष में ख्वाजा अहमद अब्बास और जयदेव को भुलाना ठीक नहीं था. निर्माता, निर्देशक, लेखक होने के नाते अब्बास का जिक्र करना अति आवश्यक था. सबसे बड़ी बात यह है कि वे पत्रकारिता के स्तंभ थे. जयदेव भी पुराने दिग्गज संगीतकार थे. उनके मीठे संगीत को सुनकर आज भी दिल हिलोरे लेने लगता है.

—राजेंद्र परमार, इंदौर (म.प्र.)

■ बीता वर्ष सारा पतझड़ में ही बीत गया, बसंत ऋतु कभी नहीं आई. विस्फोटक आबादी वाले प्रजातांत्रिक देश में छोटी-मोटी घटनाएं तो आम बात है पर सन '87 में जो भूकंप आए वे दोस्ती-दुश्मनी, वफादारी-गद्दारी और राजनैतिक स्वार्थों की वजह से हुए. आपसी गुटबंदी और संघर्ष की वजह से सरकार का नैतिक पतन, तथा आम जनता के साथ विश्वासघात हुआ है.

—सांवल सिंह यादव, जयपुर (राज.)

किसका कल्याण?

कसौटी के अंतर्गत 'लुटाने का अर्थशास्त्र' (15 जनवरी) पढ़ा. सत्तारूढ़ पार्टी कर्ज मेलों को जिस तरह इस्तेमाल करके समाजवाद के ऊंचे आदर्शों को विकृत कर रही है, वह बेहद शर्मनाक और निंदनीय है. अब राज्य जन-कल्याणकारी न होकर इंका का कल्याण करने वाला हो गया है. उफ! कैसे लोगों के हाथ में आ गई है राजसत्ता!

—नरेंद्र सिंह, नई दिल्ली

■ आज सरकारी पार्टी का छोटे-से-छोटा नेता भी बैंक प्रबंधकों को धमकाकर ऋण पाने या दिलवाने में सफल हो जाता है. लेकिन वसूली के समय बैंक अधिकारियों को अंगूठा दिखा दिया जाता है. रही सही कसर देवीलाल की कर्ज माफी वाली घोषणा ने पूरी कर दी है जिससे ऋण न चुकाने की प्रवृत्ति को और प्रोत्साहन मिलेगा.

—पवन गोयल, श्रीगंगानगर (राज.)

देश-चालक की सनकें

'सैर की सनक' (15 जनवरी) पढ़कर लगा जैसे राजीव विमानचालक के जमाने की अपनी इच्छाओं कों भूल नहीं पाए हैं. पर उन्हें याद रखना चाहिए कि वे अब देश-चालक हैं और देश भी ऐसा जिसके लिए इस तरह की फिजूलखर्ची और एय्याशी बूते के बाहर की बात है. बेहतर है वे इन सनकों को भूल जाएं.

—पीतांबर दत्त, अंबाला छावनी (हरियाणा)

■ आपने प्रधानमंत्री की सरिस्का अभयारण्य में कुछ घंटों के सैर-सपाटे का बहुत अच्छा विश्लेषण किया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के नाम पर सैर-सपाटे के लिए करीब 50 लाख रुपए खर्च कर दिए गए और वह भी ऐसे समय जब देश और राज्य में दो साल से लगातार सूखे की स्थिति है. फिर कभी ऐसा किया गया तो हमें इसके विरुद्ध आवाज उठानी ही होगी.

—मुकेश कुमार छीपा, जयपुर (राज.)

कुर्सी का खेल

खास रपट 'मंझधार में राजनीति' (15 जनवरी) पढ़ी. विडंबनाओं के वर्ष में एमजीआर के निधन से तमिलनाडु की

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

राजनीति में विडंबनात्मक स्थिति ही पैदा हो गई है. अन्नाद्रमुक दोफाड़ हो गया है. अफसोस कि जिसे राजनीति का क-ख-ग मालूम नहीं, एमजीआर की उसी विधवा जानकी को राज्य की सर्वोच्च कुर्सी पर बिठाने के लिए ले-दे हो रही है.

—**कंचन कुमार,** गाजियाबाद (उ.प्र)

बर्बर युग की ओर

'बच्चे की बलि' (15 जनवरी) पढ़कर लगा कि लोगों में अंधविश्वास किस कदर कूट-कूट कर भरा है. बिलौनी दुखद बात है कि भौतिक लिप्सा के लिए लोग एक मासूम की बलि देने में भी नहीं हिचकते. ये पाखंड और कुरीतियां हमें सीधे बर्बर युग में ले जाती हैं.

—**श्याम मनोहर व्यास,** उदयपुर (राज.)

उन्नति या अवनति

आवरण कथा 'हर दर पर दस्तक' (31 दिसंबर) पढ़कर खुशी भी हुई और दुख भी. कंप्यूटर के प्रति हमारी बढ़ती रुचि से जहां पूंजीवाद को बढ़ावा मिलेगा, वहीं हम जैसे छात्रों का भी भविष्य भी न जाने क्या हश्र होगा. जिस तरह के उदाहरण आपने गिनाए हैं उससे समझ नहीं आता कि हम उन्नति कर रहे हैं या अवनति.

—**मनोज सूद,** कुल्लू (हि.प्र.)

■ कंप्यूटर भविष्य में हमारी जीवनशैली में अभूतपूर्व परिवर्तन का सूचक है. जिस तरह कंप्यूटर समय, परिश्रम और धन की बचत के साथ-साथ कार्य में सुंदरता और मौलिकता का प्रतीक है, उसी तरह हमें इसका उपयोग भी सुनियोजित ढंग से करना होगा ताकि देश प्रगति के सही रास्ते पर बढ़ सके.

—**संजय कुचेरिया,** कृष्णाई (असम)

■ प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हार्दिक इच्छा है कि भारत कंप्यूटरों पर सवार होकर शीघ्र ही 21वीं सदी में पहुंच जाए. आजादी के 40 साल बाद भी जिस देश के आम नागरिक की समस्या रोटी, कपड़ा और मकान की है उसे जरूरत ऐसे सुपर कंप्यूटर की है जो देशवासियों को भरपूर पानी, बिजली रोजगार, रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध करा सके.

—**सुरेश छाबड़ा,** रावतभाटा (राज.)

■ सचमुच कंप्यूटर ने जिंदगी के हर पहलू को प्रभावित किया है; लेकिन यह भी निश्चित है कि चरखों और बैलगाड़ियों की प्रमुखता वाले देश में इससे बेरोजगारी भी ज्यादा बढ़ेगी.

—**जगमोहन वशिष्ट,** चौरवंडी (दिल्ली)

■ देश के विकास में कंप्यूटर का इतना बड़ा हाथ देखकर दांतों तले अंगुली दबानी पड़ी. वह दिन दूर नहीं कि हमारे देश में कंप्यूटर का ही बोलबाला हो जाएगा. आवश्यकता इस बात की है कि देश की जनता कंप्यूटर के साथ सही तालमेल बैठा सके. पर डर यही लगता है कि कहीं भ्रष्ट नेता इनका उपयोग कालाबाजारी में न करने लगें.

—**सुजीत कुमार झा,** चतरा (बिहार)

लोकतंत्र का मजाक

'वैभव का प्रदर्शन' (31 दिसंबर). यह शायद 20वीं सदी की सबसे खर्चीली शादी है. इसमें दोनों राजा-महाराजों ने अपनी शानो-शौकत को दुनिया के सामने दर्शाया है. यह उनका व्यक्तिगत मामला तो है पर जहां जनता रोटी-रोटी को तरसती है वहीं दूसरी ओर सोने की थाली में भोजन परोसा जाए, यह ठीक नहीं.

—**कमल नयन 'अंबष्ठ',** घुघरीटांड (बिहार)

■ इस शादी की जितनी आलोचना की जाए कम है. यदि यही करोड़ों रुपए किसी उद्योग में खर्च किए जाते तो देश के उत्पादन में वृद्धि हो जाती और लोगों को रोजगार की सुविधाएं मिलतीं. सरकार को संविधान में एक अनुच्छेद और जोड़ना चाहिए, जिसमें शादियों में किए जाने वाले खर्च की सीमा निर्धारित की जाए.

—**मिट्ठू संजीव,** करनाल (हरियाणा)

■ शाही शादी में वैभव का खुला प्रदर्शन भारतीय लोकतंत्र की हत्या के समान है. गरीबी हटाओ का नारा देने वाली सरकार सब कुछ चुपचाप देखती रही. लगता है आज फिर सामंतवाद लोकतंत्र पर हावी हो गया है. गरीबी हटाओ का नारा मात्र एक छलावा लगता है.

—**श्रवण कुमार अग्रवाल,** कटिहार (बिहार)

■ राजा-महाराजाओं की 'सुविधाएं एवं संबोधन' संवैधानिक संशोधन के तहत 17 साल पहले समाप्त कर दिए गए. ऐसी हालत में संवैधानिक हैसियत रखने वाले और भारतीय संविधान की मानरक्षा की शपथ से बंधे रेल राज्यमंत्री माधवराव सिंधिया का समाजवादी भारत में राजसी परंपराओं को पुनर्जीवित करना क्या भारतीय संविधान का मान मर्दन नहीं है?

—**अर्चना दीक्षित,** वर्धा (महाराष्ट्र)

■ अफसोस है कि भारत जैसे देश में जहां बहुत से लोगों को खाना तक नसीब नहीं होता वहां लाखों रुपए विवाह के नाम पर उड़ा दिए जाते हैं.

—**द्वारिका प्रसाद,** डिब्रूगढ़ (असम)

परिणाम भयंकर होंगे

आपने कंप्यूटरीकरण के भयंकर परिणामों की ओर संकेत नहीं किया है. सिमटते काम से बढ़ती बेरोजगारी की चर्चा भी होनी चाहिए. सरकारी आंकड़ों के अनुसार तीन करोड़ व गैर-सरकारी आंकड़ों के अनुसार 10 करोड़ शिक्षित बेरोजगारों और लगभग 15 करोड़ ग्रामीण बेरोजगारों (कुल 25 करोड़) का भविष्य क्या होगा?

—**विमल मालाकार,** बरारी (बिहार)

■ कंप्यूटर ने हर क्षेत्र में तूफानी क्रांति लाकर मानव जीवन के ढर्रे को ही बदल डाला है. समय की बचत करने के साथ-साथ मानसिक तनाव से भी मुक्ति दिलाने वाले इस यंत्र का प्रयोग सरकार पश्चिमी राजस्थान के दूर-दराज इलाकों में भी करे तो निस्संदेह 19वीं शताब्दी में जा रही ग्रामीण जनता में एक बहुत बड़े बदलाव की संभावना है.

—**ईश्वर लाल संगतानी,** बालोतरा (राज.)

रंगीनमिजाज नेता

कसौटी के अंतर्गत 'जरूरी है मर्यादाओं की पहचान' (31 दिसंबर) में सार्वजनिक जीवन की पवित्रता के अनेक आयामों को उद्घाटित करना एक ज्वलंत विचार है. महानता की कसौटी सादगी है. रंगीनमिजाजी और यारबाजी में मशगूल हमारे प्रधानमंत्री अगर इस सिद्धांत के साथ तादात्म्य बिठाते तो शायद उनकी दिनचर्या और जीवनशैली में बदलाव आ जाता.

—**शिवपूजन तिवारी,** उन्नाव (उ.प्र.)

■ देश की काफी जनसंख्या अभी भी गरीबी रेखा के नीचे जी रही है और प्रधानमंत्री महाराजा जैसी जिंदगी जी रहे हैं. एक लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री के लिए यह शोभा नहीं देता.

—**तारकेश कुमार ओझा,** खड़गपुर (प.बं.)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रुपयों की बात खास सुरक्षा के साथ!

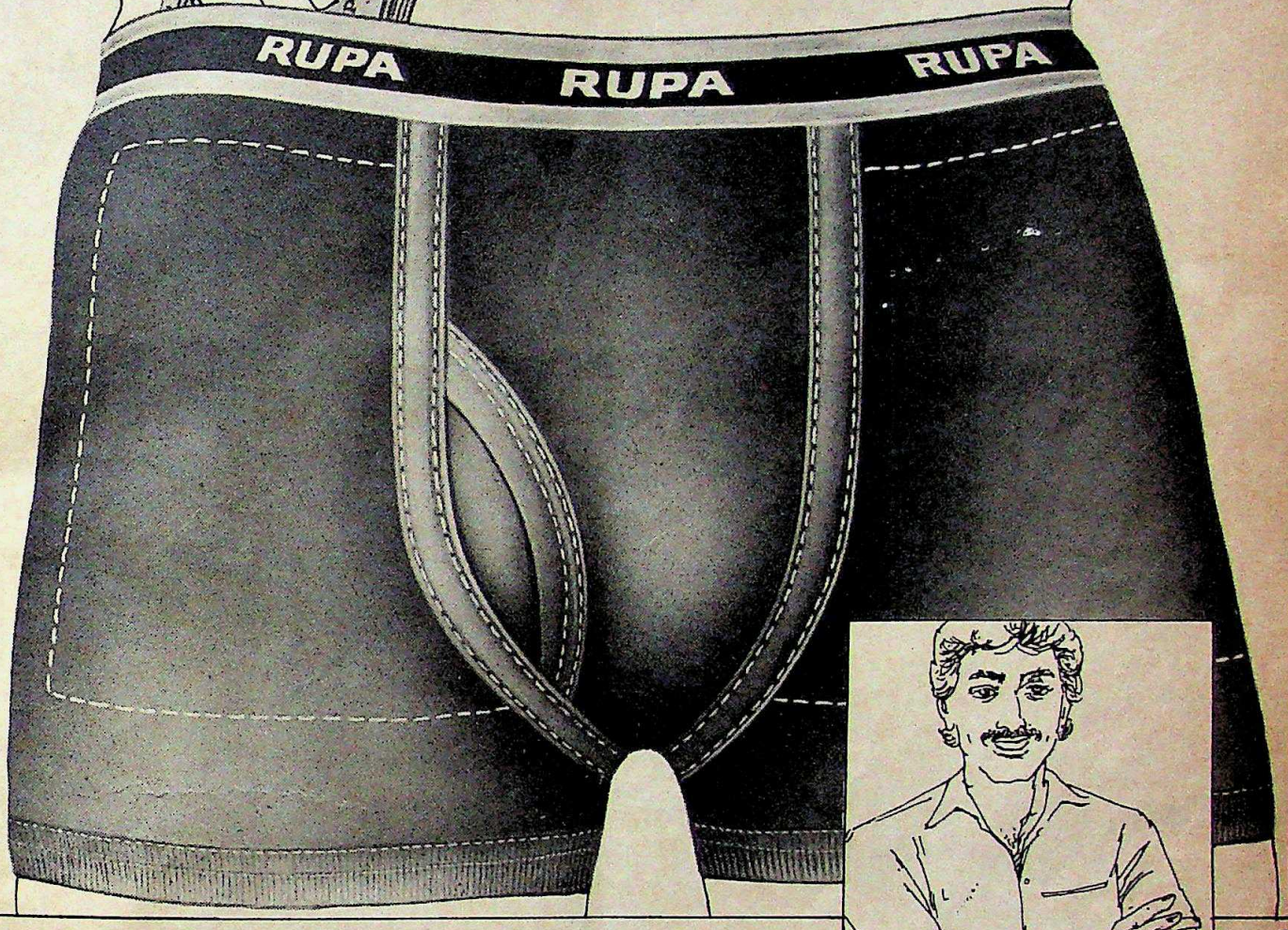

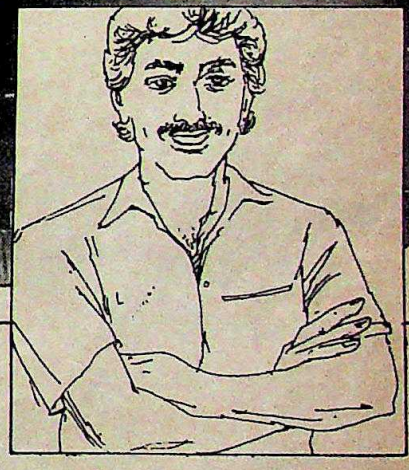

DPS/BH-875

RUPA® पॉकेट जांघिये

अब चिन्ता छोड़िये, निश्चिंत रहिये—अपने नगद रुपयों को भीतरी पॉकेट में डालकर आराम की सांस लीजिये। रुपा पॉकेट जांघिया आयातित रबर की इलास्टिक से बना आपकी कमर के लिए पूर्णतः आरामदेह है। रेशम सी कोमलता का अहसास और फिटिंग लाजवाब। विभिन्न आकर्षक रंगो में उपलब्ध।

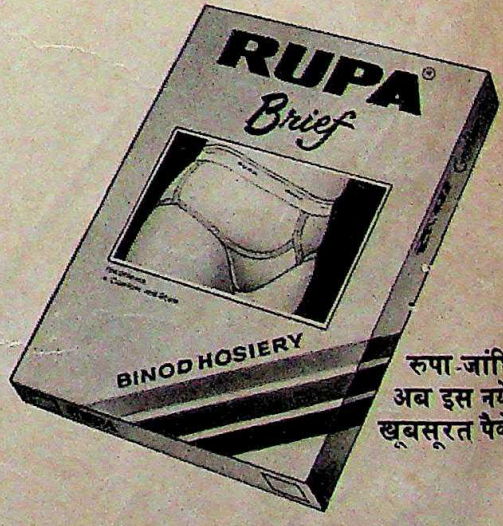

रुपा-जांघिया
अब इस नये
खूबसूरत पैकेट में

रूपा – लाखों परिवार, पहनें बार बार

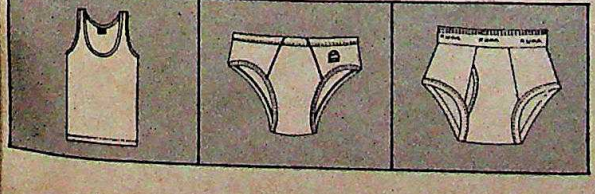

बिनोद होसियारी, कलकत्ता ७०० ००७ का एक उत्कृष्ट उत्पादन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

■ किफायतपसंद प्रधानमंत्री को आपने फिजूलखर्च और रंगीनमिजाज कह डाला. राजीव गांधी की किफायतपसंदगी का ताजा नमूना नए साल के कार्ड न भेजने का उनका ताजा आदेश है. सरिस्का वगैरह जैसे कार्यक्रमों पर दो-चार करोड़ खर्च हो भी गए तो क्या नए साल के कार्ड न भेजने से कई हजार रुपए की बचत नहीं होगी?

—**ज्ञान प्रकाश,** गोंडा (उ.प्र.)

वाह रे समाजवाद

विशेष लेख 'बड़े लोगों की जेब गरमाई' (31 दिसंबर) पढ़ा. मुख्यमंत्री राहत-कोष गरीबों, जरूरतमंदों के लिए होता है पर इससे लाभ अमीरों को मिल रहा है. विडंबना तो यह है कि एक ही रोग के लिए अमीर को तो बीस हजार मिल सकता है मगर गरीब को मात्र दो सौ रुपए. मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा को यह वोरा को यह उत्तर देते हुए शर्म आनी चाहिए कि ऐसे मामले कम आते हैं.

—**अतुल कुमार खंडेलवाल,** पट्टी (उ.प्र.)

■ वोरा जी अपनों-अपनों को रेवड़ियां बांट रहे हैं. वास्तव में मुख्यमंत्री इस तरह राहत कोष का मजाक बनाते रहे तो जनता का उन पर से विश्वास उठ जाएगा.

—**अनमोल सुरोलिया,** दौलतगंज (म.प्र.)

■ मुख्यमंत्री राहत कोष सूखा, बाढ़, प्राकृतिक विपदाग्रस्त, अभावग्रस्त व्यक्तियों को छोड़कर सत्ता के गलियारे के निकट हर व्यक्ति को राहत मुहैया करा रहा है. इससे मुख्यमंत्री राहत कोष ही नहीं, प्रधानमंत्री राहत कोष पर भी प्रश्नचिन्ह लग गया है. जब प्रदेश के ऐसे हालात हैं तो हो सकता है देश के भी ऐसे ही हों.

—**गुरुदेव सिंह भाटिया,** सेधवा (म.प्र.)

फिर जिम्मेदारी कैसी

'राजनैतिक खानापूरी' (31 दिसंबर) पढ़ा. क्या आयोग सिर्फ सरकार को बाइज्जत बरी करने के लिए ही बनाया गया था? आयोग का आर्थिक अपराधियों को खोजने के काम को राष्ट्रद्रोही करार देना उचित है? मामला तो फिर वहीं पहुंच गया. न तो आर्थिक अपराधी पकड़े गए और न ही विदेशों में धन इकट्ठा करने वाले नेता. अगर प्रधानमंत्री सच्चे हैं तो वे इन आर्थिक अपराधियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं करते?

—**राजेश खन्ना,** अमृतसर (पंजाब)

■ सरकार द्वारा इस आयोग की रिपोर्ट को अभूतपूर्व तरीके से उछाला जाना एक घोर आश्चर्य की बात है. सामूहिक ज़िम्मेदारी का गला घोंट दिया गया है. यदि हम मान लें कि सरकार को फेयरफैक्स की नियुक्ति का पता नहीं था तो क्या 'सामूहिक जिम्मेदारी' 'दोष' और नहीं बढ़ जाता है कि खुद प्रधानमंत्री को पता नहीं कि उनकी सरकार में क्या हो रहा है? इस विषय पर आयोग ने कलम क्यों नहीं चलाई?

—**उर्षा तिवारी,** बसंतपुर (उ.प्र.)

■ आयोग का एकतरफा निष्कर्ष ही इसकी विश्वसनीयता और निष्पक्षता पर प्रश्नचिन्ह लगाता है. प्रश्न यह नहीं है कि विदेशी एजेंसी फेयरफैक्स की नियुक्ति उचित है या नहीं बल्कि जरूरी यह है कि देशद्रोही लुटेरों को सजा दी जाए जिन्होंने विदेशी बैंकों में काला धन जमा कर रखा है.

—**सुनील कुमार सिंह,** पटना (बिहार)

■ आयोग ने सचाई ढूंढ़ निकालने के बजाय वी.पी. सिंह और उनके सहयोगियों को दोषी ठहराया. यह तो सरासर गलत है. आयोग यही कुछ करते रहे तो लोगों का विश्वास उन पर से उठ जाएगा.

—**गोविंद कुरडकर,** भिवापुर (महाराष्ट्र)

सिनेरारिया श्वाबे
चक्षुउपचार का विश्वसनीय होमियोपैथिक नुस्खा

"जब कभी रसोई में मुझे ज्यादा देर काम करना पड़ता है तो आंखों में जलन और खुजलाहट होने लगती है, अतः मैं हफ्ते में तीन बार सिनेरारिया श्वाबे डालती हूँ।

"जब से मैंने सिनेरारिया श्वाबे इस्तेमाल करना शुरु किया है, मेरा मोतिया बिंद का बढ़ना काफी कम होने लगा है"

"रोज रात होमवर्क के बाद मम्मी मेरी आँखों में सिनेरारिया श्वाबे की दो बूँदें डालती हैं वह कहती हैं इससे मेरी आँखें स्वस्थ रहती हैं।"

उनकी राय मानिये जिन्होंने इससे फायदा पाया है:—

सिनेरारिया मैरिटिमा सवकस श्वाबे एक भरोसेमंद होमियोपैथिक औषधि है जो दर्द, जलन, खुजलाहट जैसी आँखों की आम तकलीफों में बहुत फायदेमंद है और मोतियाविंद रोकने में मदद करती है।
दुनिया भर में घर परिवारों में पिछले 20 सालों से इसका उपयोग किया जा रहा है

* परिवार के हर सदस्य के लिये उपयोगी,
* आँखों को स्वस्थ रखती है,
* आँखें दुखने व मोतिया बिंद की आजमायी हुई औषधि,

SCHWABE श्वाबे
सिनेरारिया मैरिटिमा सवकस
विश्वसनीय चक्षु, उपचार

डा० विलिमर श्वाबे आफ वेस्ट जर्मनी की देन
दवाइयों की सभी बड़ी दुकानों पर उपलब्ध।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

इंडिया टुडे
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कसौटी

हावी है परिवारवाद

करीब तीस साल हुए जब राष्ट्रनिर्माताओं ने जमींदारी प्रथा कानूनन समाप्त कर दी थी. और करीब बीस साल हुए जब स्वघोषित 'प्रगतिवादी' प्रधानमंत्री ने राजे-रजवाड़ों के लिए खुली थैलियों के मुंह बंद किए थे. लेकिन भारतीय राजनीति सामंतशाही के उच्छिष्ट—वंश परंपरा—से आज तक मुक्त नहीं हो पाई है.

जवाहरलाल नेहरू ने शक्तिशाली सामंतों को अपनी पैतृक रियासतों पर से अपने अधिकार छोड़ने को मजबूर तो किया लेकिन खुद अपनी बेटी को अपना उत्तराधिकारी बनने के लिए तैयार करते रहे. और इंदिरा गांधी अपनी नई 'प्रगतिशील' नीतियों को लागू करने के लिए पार्टी के खुर्राट नेताओं से भिड़ीं जरूर लेकिन यह व्यवस्था भी करती रहीं कि वे अपने चारों ओर सत्ता का जो तामझाम तैयार कर रही हैं वह उनके 'राजकुमारों' को ही मिले.

रेखाचित्र: अजीत नाइनन

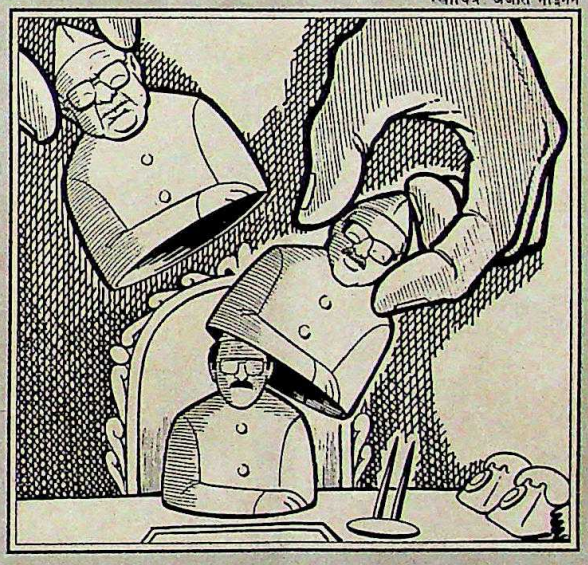

विडंबनाओं का यह सिलसिला जैसे अनंत है. और ऐसा भी नहीं है कि साफ-सुथरे लोकतंत्र में वंश परंपरा इसलिए पनप रही है क्योंकि उत्तराधिकारियों को बहुत सोच-समझकर तैयार किया जा रहा हो. पिछले पखवाड़े तमिलनाडु में एम.जी. रामचंद्रन की 62 वर्षीया विधवा को मुख्यमंत्री पद पर स्थापित कर दिया गया. उनकी अन्नाद्रमुक पार्टी के बड़े नेताओं ने खुद दावा करने के बजाय उनके परिवार में ही उत्तराधिकारी तलाशने का आसान रास्ता चुना. जानकी को इस पद के योग्य बनाने की पहले कभी कोई कोशिश नहीं की गई थी. यानी मामला चाहे राजीव गांधी का हो या फारूक अब्दुल्ला का या बंसीलाल, देवीलाल और प्रताप सिंह कैरों के बेटों का, सामंती प्रथा जैसे स्थापित मूल्य बन गया है.

लेकिन यह सब लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की आड़ में चल रहा है. इसलिए अपनी राज्य-व्यवस्था और लोकतांत्रिक संस्थाओं की प्रौढ़ता पर संदेह होता है. सत्तासीन परिवारों की पत्नियां, विधवाएं और बेटे उत्तराधिकार की बागडोर जिस आसानी से संभाल लेते हैं वह जितना खतरनाक है उतना ही विशाल राष्ट्र की क्षमताओं का अपमान भी. यह प्रवृत्ति ऊपर से लेकर नीचे तक विद्यमान है. और इसके उदाहरण भी अनेक हैं. केंद्रीय राज्यमंत्री चंद्रशेखर सिंह के निधन के बाद सत्ता पार्टी ने उनकी पत्नी को उपचुनाव में खड़ा कर दिया, इंका के ख्यातिनाम प्रवक्ता श्रीकांत वर्मा गए तो उनकी जगह उनकी पत्नी को राज्यसभा में बिठा दिया गया, जानकी बल्लभ पटनायक ओडीसा के मुख्यमंत्री बने तो खाली हुई लोकसभा सीट उनकी पत्नी जानकी ने भरी, वसंत दादा पाटील जब राज्यपाल बना दिए गए तो उनके चुनाव क्षेत्र सांगली से चुनाव लड़ाने के लिए पार्टी को उनका बेटा ही उपयुक्त लगा, और इंका के बुजुर्ग नेता कमलापति त्रिपाठी की सारी जद्दोजहद अपने बेटे को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाने की ही रही है.

परिवारवाद के इस संक्रामक रोग से कोई भी पार्टी अछूती नहीं रही है. इंका के वंशानुगत शासन के खिलाफ ढिंढोरा पीटती रहने वाली विपक्षी पार्टियों का इतिहास भी इस मामले में बहुत बेदाग नहीं रहा है. आंध्र प्रदेश में नंदमूरि तारक रामराव तो अपने बेटे और दामाद दोनों को तैयार करते रहे हैं. और अंततः उन्होंने अपने बेटे बालकृष्ण को अपना उत्तराधिकारी घोषित भी किया.

ये सब गहरी बीमारी के ही लक्षण हैं. अधिकांश पार्टियां यह आसान रास्ता इसलिए चुनती हैं क्योंकि नेतृत्व के संघर्ष को झेलने का संगठनात्मक ढांचा या माद्दा उनके पास नहीं होता. इसलिए वंश परंपरा को तरजीह दी जाती है, भले ही उसके कारण साधारण परिवारों से आए महत्वाकांक्षी पार्टी नेता उपेक्षित हो कर असंतुष्ट होते हों. इस तरह की अदूरदर्शिता पहले आत्मघाती साबित हो चुकी है. राजीव गांधी, और चरण सिंह के सुपुत्र अजीत सिंह ने पार्टी कमान संभालने के बाद पार्टी में जिस तरह असंतोष को जन्म दिया है उससे यह और भी उजागर होता है.

जो पार्टियां रियासत की तरह चलाई जाती हैं उनका हश्र यही हो तो क्या अचरज! सर्वेसर्वा बन चुके नेता के दिवंगत होते ही नेतृत्व के लिए जो झगड़ा चलता है वह इसी तथ्य को उजागर करता है कि पार्टी में नेतृत्व की दूसरी स्वाभाविक पंक्ति तैयार नहीं की जाती है. बल्कि वास्तव में नेता ही नहीं चाहते कि उनकी पार्टी एक अधिकार-संपन्न पार्टी बने क्योंकि इससे उनकी वंश परंपरा के समाप्त होने का खतरा होता है. नतीजा यह होता है कि राजनीति पर वे पार्टियां हावी रहती हैं जिनमें लोकतंत्र नाममात्र को नहीं होता, पदाधिकारी चुने नहीं नामजद किए जाते हैं और नेता जैसे महाभिषेक करके बनाए जाते हैं.

कहा जा सकता है कि ये नेता भी आखिर उसी भारतीय सामाजिक-राजनैतिक माहौल के अंग हैं जिसमें परिवार नामक संस्था के लिए भारी कमजोरी विद्यमान है. राष्ट्रीय राजनीति में अरुण नेहरू अगर अचानक लोकप्रिय हो गए तो इसका बहुत कुछ श्रेय उनके नाम के साथ जुड़े महिमामंडित 'नेहरू' शब्द को जाता है. श्रीमती इंदिरा गांधी अगर चुनाव नामांकन पत्र भरते हुए इंदिरा नेहरू गांधी नाम लिखने पर जोर देती थीं तो इरादा नेहरू और गांधी दोनों की लोकप्रियता का लाभ उठाने का होता था.

ऐसे सामाजिक ढांचे में केवल राजनीतिकों के जरिये परिवर्तन लाना संभव नहीं है. लोकतंत्र पर लगा परिवारवाद का कलंक तभी धुलेगा जब लोग इस पर सवाल उठाने लगेंगे. सौभाग्य से इसके कुछ संकेत दिखने लगे हैं. हरियाणा में देवीलाल को व्यापक दबाव के कारण ही अपने बेटों को लोकदल (ब) के नेतृत्व से हटाना पड़ा. दूसरे राज्यों में भी लोग अगर इससे सबक लें तो भारतीय राजनीति इस कलंक से मुक्त हो जाए और देश को नेतृत्व के लिए चंद गिने-चुने परिवारों में ही प्रतिभाएं ढूंढने से निजात मिल सकेगी.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अबु, पैट्रियट

● मुझे अपने रिश्तेदारों को महत्वपूर्ण पदों पर रखने में कोई बुराई नजर नहीं आती.
■ **देवीलाल,** *रविवार*

● देवीलाल ने राजशाही मचा रखी है. सऊदी अरब समझ लिया है हरियाणा को.
■ **बुद्धप्रिय मौर्य** (महासचिव, लोकदल-ब), *जनसत्ता*

● अब 1977 से जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर जी ही हैं. क्या इस पार्टी में वही एक आदमी हैं, बाकी सब चूहे?
■ **मधु लिमये,** *दिनमान*

● अब कोई राजीव गांधी को मि. क्लीन नहीं कहता. अब तो कांग्रेस के लोग भी इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करते.
■ **लालकृष्ण आडवाणी,** *आज*

● राजनीतिक तो सिर्फ लाउडस्पीकर होते हैं.
■ **मेनका गांधी,** *धर्मयुग*

● क्या मैं प्रधानमंत्री का क्लर्क था कि छोटी-से-छोटी बात के लिए भी उनके पास दौड़ता?
■ **विश्वनाथ प्रताप सिंह,** *फ्रंटलाइन*

● सोनिया ने मुझसे कहा कि संसद में आप मेरे बारे में झूठी बातें कहते रहे हैं, मैं आपका हश्र देख लूंगी.
■ **पी. उपेंद्र,** *संडे आब्जर्वर*

● मेरी पत्नी किसी को धमकी नहीं देती.
■ **राजीव गांधी,** *टाइम्स ऑफ इंडिया*

● इंका की मदद से सरकार बना कर मैं राजनैतिक मौत नहीं चाहता.
■ **प्रकाश सिंह बादल,** *ऑनलुकर*

● आपके कुशल नेतृत्व में बिहार ने सचमुच शिक्षा के क्षेत्र में चहुंमुखी विकास किया है. आप सचमुच इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं.
■ **संपादक,** *साप्ताहिक हिंदुस्तान* (बिहार के शिक्षामंत्री से बातचीत में)

● मैं यह भूलने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं गावसकर की जगह खेल रहा हूं.
■ **अरुण लाल,** *संडे मेल*

● जब तक लोग याद नहीं दिलाते, मैं अपनी उम्र के बारे में कभी नहीं सोचता.
■ **देवानंद,** *स्टार ऐंड स्टाइल*

● फिल्म उद्योग में श्रीदेवी को छोड़ कोई अभिनेत्री नहीं है जिससे मुझे कोई खतरा हो.
■ **अमृता सिंह,** *स्टारडस्ट*

भरिए

यह कूपन और
अपनी चहेती आवाज़ सुनिए:
बच्चे की खिलखिलाहट

हंसी-खुशी और मौज-मस्ती बच्चों के लिए उतनी ही ज़रुरी हैं जितने ज़रुरी हैं खाना-पीना और हवा. और डिस्नी टुडे लेकर आया है यही मस्ती... यही मज़े.
बस तो फिर यह कूपन भर दीजिए और हर एक को खुश कर दीजिए.

आकर्षक छूट का लाभ उठाईये.

कूपन निम्नलिखित पते पर भेजें:
लिविंग मीडिया इंडिया (प्रा.) लि.
सबस्क्रिपशन डिपार्टमेंट
थॉमसन प्रेस बिल्डिंग
पो.बॉ. न० 69, दिल्ली-मथुरा रोड
फ़रीदाबाद - 121 007 (फ़रीदाबाद)

मुझे अपने बच्चे के लिए सबस्क्रिपशन चाहिए. यह रहा मेरा ☐ सालानाः रु. 78/- ☐ छह महीने काः रु. 40/- हिन्दी प्रति के लिए सबस्क्रिपशन मैं भुगतान चैक/मनी आर्डर/डिमांड ड्राफ्ट न. _____ द्वारा कर रहा हूँ. कृप्या प्रति निम्नलिखित नाम व पते पर भेजें:

नाम _____
उम्र _____ लिंग _____
डाक-पता _____
_____
_____
विद्यालय _____
माता-पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर _____
कृप्या भुगतान लिविंग मीडिया इंडिया (प्रा.) लि. के नाम पर बनाएं.

Walt Disney Comics
डिस्नी टुडे
अब उपलब्ध हर पखवाड़े
हिन्दी और अंग्रेज़ी में

MILESTONES/DT/114 Hin a

© 1987 THE WALT DISNEY CO., USA.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सोनिया का नया अवतार

● इस बार हैरान होने की बारी भारतीय नौसेना के उन नौसैनिकों की थी जिनके जिम्मे लक्षद्वीप में छुट्टियां मनाने वाले प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी को विमानवाहक पोत 'विराट' से द्वीपों की सैर कराना था. हैरानी की बात यह थी कि जिस अति विशिष्ट महिला को अब तक उसके रूखेपन और भावशून्य चेहरे के लिए जाना जाता था उसने वहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों और लंच के दौरान हंसी की फुलझड़ियां बिखेर दीं. जिन नौसैनिक अधिकारियों को पहले सोनिया गांधी से दूर रहने की ताकीद की गई थी वे उनके इस नए रूप से चकित थे.

जिस समय राजीव वरिष्ठ नौसैनिक अधिकारियों के साथ बातचीत में व्यस्त थे उस समय सोनिया नौसैनिकों के साथ लतीफे सुनने-सुनाने में मशगूल थीं. उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम के कलाकारों के पास जाकर उन्हें भी बधाई दी. गुफ्तगू का यह दौर तकरीबन दो घंटे चला और इस बीच उन्होंने अब तक देखे गए अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बारे में भी अपनी राय

जतायी. कई नौसैनिक तो अभी भी इसे सपना समझ रहे हैं. लेकिन लोगों में इस तरह घुलने-मिलने के उनके इस अचानक प्रयास के बारे में एक नौसैनिक अधिकारी का कहना था कि वे अब शायद यह सिद्ध करने में लगी हुई हैं कि उनमें ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से उनसे डरा जाए. विराट पर उस समय मौजूद एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना था, "शायद यह पहला मौका था जब सोनिया गांधी ने देश के प्रधानमंत्री की पत्नी के नाते सही भूमिका निभाई है."

'अर्जुन' पर महाभारत

● लगता है कि अब भारतीय थल सेना के यंत्रीकृत सेना महानिदेशालय (डीजीएमएफ) और रक्षा अनुसंधान व विकास विभाग

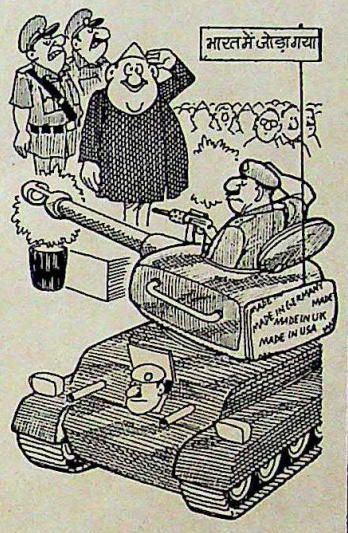

सभी कार्टून: अजीत नाइनन

(डीआरडीओ) के बीच एक नई जंग छिड़ने जा रही है. विवाद अर्जुन टैंक पर है जिसे थलसेना के लिए विकसित किया जा रहा है.

हाल ही में डीआरडीओ ने घोषणा की कि इस बार की गणतंत्र दिवस परेड का मुख्य आकर्षण अर्जुन होगा. जबकि सच यह है कि न तो इसके असली उपभोक्ता डीजीएमएफ ने इसके परीक्षण पूरे किए हैं और न उसने इस प्रदर्शन की ही सहमति दी है. सेना की परंपरा के अनुसार किसी भी हथियार के सार्वजनिक प्रदर्शन से पहले उसके उपभोक्ता विभाग समेत अन्य कई तकनीकी समितियों की सहमति लिया जाना जरूरी है. अभी पिछले ही महीने रक्षा मुख्यालय में एक गुप्त रिपोर्ट में अर्जुन टैंक की खामियों का लेखाजोखा पेश किया गया था. इसके अलावा अभी तक आवड़ी में इस टैंक के केवल 10 प्रयोगात्मक नमूने ही तैयार किए जा सके हैं. ऐसा लगता है कि टैंक के प्रदर्शन के इस फैसले के पीछे इस आलोचना को शांत करना है कि इसके विकास में अत्यधिक समय और पैसा बरबाद किया जा रहा है.

तिवारी के तेवर

● वित्त मंत्रालय इन दिनों अपनी राजस्व वसूली और खुफिया एजेंसियों में, जबरदस्त बदलाव की तैयारी में है. यह तैयारी पिछले महीने केंद्रीय उत्पाद कर और सीमा शुल्क बोर्ड के धांसू अध्यक्ष ज्योतिर्मय दत्ता के अपमानजनक निष्कासन के समय से ही चल रही है. अपने सेवाकाल की बढ़ोतरी के इस दौर में दत्ता को इसलिए चलता किया गया कि उन्होंने वित्त मंत्रालय से अखबारों में छपे एक समाचार का खंडन करने की जिद की थी. इस समाचार में दत्ता पर यह आरोप लगाया गया था कि इस्पात के आयात पर सीमा शुल्क तय करने की प्रक्रिया में उन्होंने सरकारी खजाने को 100 करोड़ रुपए का घाटा करवा दिया. मंत्रालय द्वारा खंडन जारी न किए जाने पर दत्ता ने विरोध स्वरूप इस्तीफा दे दिया.

दत्ता के स्थान पर किसी और अधिकारी को तैनात करने के सिलसिले में अब तक की गई खोज बेकार रही है. इन दिनों तिवारी किसी ऐसे धांसू अफसर की खोज में हैं जो दत्ता की ही तरह बड़े

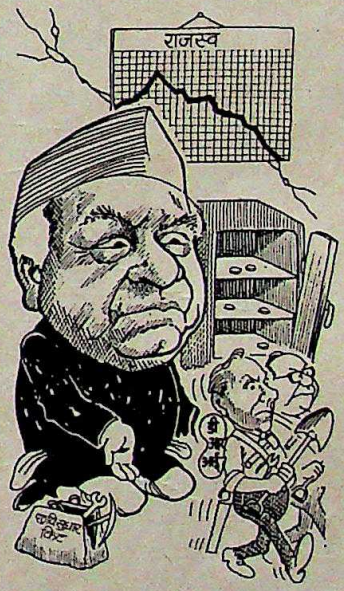

औद्योगिक घरानों पर छापे मारकर मंत्रालय की डूबती साख को बचा सके. इसी नजरिये से उन्होंने राजस्व गुप्तचर निदेशालय (डीआरआई) के खूंखार मुखिया वी.वी. कुमार को बोर्ड में सदस्य (उत्पाद कर) नियुक्त किया और पी.के. कपूर को डीआरआई का मुखिया बनाया था. अपने इस अभियान के अंतर्गत तिवारी अब बजट से पहले ही प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जैसे संगठनों में अपने भरोसे के अफसरों को ही तैनात कर देना चाहते हैं.

चरणचिन्हों पर....

● ऐसा नहीं कि छुट्टियां मनाने का फैशन केवल प्रधानमंत्री तक ही सीमित हो. अपने नेता के चरणचिन्हों पर अब उनके मंत्रियों ने भी

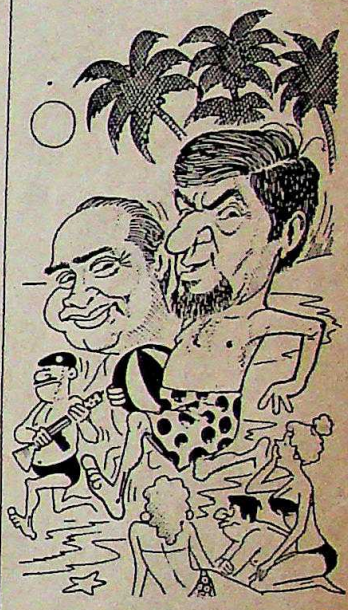

चलना शुरू कर दिया है. अभी राजीव ने बंगाराम टापू पर पांव रखा ही था कि उनके मंत्रिमंडल के कुछ मंत्रियों ने भी अपनी-अपनी सैरगाहों की ओर कूच कर दिया.

नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री जगदीश टाइटलर और विदेश राज्यमंत्री एदुआर्दो फिलेरियो ने केरल के कोवलम समुद्र तट पर डेरा जमाया तो प्रधानमंत्री सचिवालय के अफसरों और उनके व्यापारी दोस्तों ने गोवा के समुद्रतट की रेत में धूनी रमाई. इसी दौरान इंका के एक जाने-माने महासचिव ने राजस्थान के उसी सरिस्का अभयारण्य में अड्डा जमा लिया जहां पिछले दिनों राजीव ने अपनी विवादास्पद मंत्रिमंडलीय बैठक की थी. अपनी इन छुट्टियों से लौटने के बाद महासचिव का चहकते हुए कहना था, "मुझे तो पहली बार समझ आया कि मेरे जैसे राजनेता पर छुट्टियों का क्या असर हो सकता है. अब देखना हम सब लोग पहले से कितना अधिक रचनात्मक होने जा रहे हैं." लगता है पूरे देश को इस रचनात्मक प्रदर्शन के लिए सांस रोके रखनी होगी.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आ गया इंस्पेक्टर

■ मिनिस्टर, कलेक्टर और इंस्पेक्टर की तिकोनी धुरी पर चलने वाली भारतीय व्यवस्था में इन तीन 'टरों' का अच्छा-खासा दबदबा है. हालत यह है कि इनमें से एक के तेवर बदलते ही लोगों के

कार्टून: अनिल शर्मा

दिलों की धड़कनें असामान्य हो जाती हैं. यही कारण था कि उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर के एक कस्बे में पिछले दिनों एक सर्राफा बाजार की धड़कनें कुछ देर के लिए जाम होकर रह गईं.

वहां के मुहम्मदापुर कस्बे में अचानक ही खबर फैल गई कि कस्टम इंस्पेक्टर कस्बे के दौरे पर आ निकला है. बस फिर क्या था. चोर की दाढ़ी के तिनके ने झाड़ू बनकर ऐसी बुहार लगाई कि स्थानीय सर्राफा बाजार के शटर धड़धड़ाते हुए गिर गए. हंसते-खेलते हुए बाजार में अचानक इस तरह छायी मुर्दनी को देखकर ऐसा लगता था मानो वहां कर्फ्यू लगा दिया गया हो.

लेकिन हालत सामान्य होने में बहुत देर नहीं लगी. बहुत जल्दी ही पता चल गया कि बाजार में आने वाला इंस्पेक्टर अब रिटायर होने के कारण 'भूतपूर्व' हो चुका है और वह आर्थिक तंगी की वजह से अपनी पुरानी जान-पहचान वाले कुछ दुकानदारों से आर्थिक सहायता मांगने के लिए आया है. इस खबर ने कई दुकानदारों को इतनी राहत पहुंचाई कि उन्होंने न केवल अपने पुराने 'इंस्पेक्टर साहब' की अच्छी-खासी मेहमाननवाजी की बल्कि दूसरे दुकानदारों से चंदा इकट्ठा कर उसकी भरपूर मदद करने का पुण्य भी कमाया.

नपी-तुली गलती

■ भारतीय रेलगाड़ियों का देरी से चलना और देरी से पहुंचना इतनी आम बात हो चुकी है कि अब यात्रियों को सिर्फ तभी हैरानी होती है जब कोई रेलगाड़ी अपने ठीक समय पर कहीं पहुंच जाए. इधर पिछले कुछ समय से रेल व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में जुटे हुए अधिकारियों ने अपने विभाग की इस विशेषता को पूरी तरह ध्यान में रखा है. स्टेशनों पर लगाए जाने वाले कंप्यूटरीकृत सूचनापटों में देरी से आने वाली गाड़ियों की सूचना देने की व्यवस्था भी रखी जा रही है.

पर पिछले दिनों आंध्र प्रदेश से मिले एक समाचार को देखकर लगता है कि भारतीय रेल विभाग के ड्राइवर इस फिराक में हैं कि कंप्यूटरीकरण से पहले ढीलढाल दिखाने के जितने भी अवसर मिलें उन सभी अवसरों का पूरा लाभ उठा लिया जाए. इस समाचार के अनुसार नई दिल्ली से मद्रास जाने वाली एक एक्सप्रेस गाड़ी आंध्र के खम्माम स्टेशन पर हर रोज देरी से आने के लिए ऐसी प्रसिद्ध हो चुकी है कि गत दिनों इस गाड़ी ने रात के ठीक 9.35 बजे प्लेटफार्म पर पहुंचकर सनसनी फैला दी. खुशी में झूमते हुए कुछ यात्रियों ने तुरंत ही पास की एक दुकान से फूलों का हार खरीदकर ड्राइवर के गले में पहना दिया. अभी वे उसे

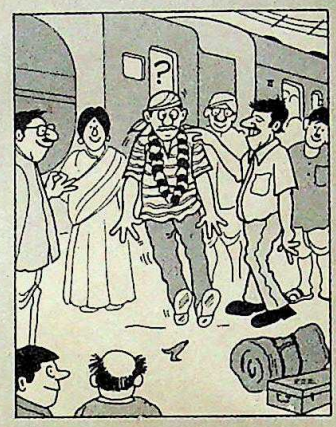

कंधों पर उठाकर उसका जुलूस निकालने की सोच ही रहे थे कि शर्म के मारे झेंपते हुए ड्राइवर ने यह घोषणा करके उनके जोश पर ठंडा पानी डाल दिया कि गाड़ी ठीक 24 घंटे लेट पहुंची है.

नाराज प्रतियोगी

■ यदि किसी प्रतियोगी के गुणों को अनदेखा करके उसे पुरस्कार के लिए न चुना जाए तो उसका नाराज होना स्वाभाविक ही है. आम तौर पर ऐसी हालत में प्रतियोगी से यही उम्मीद की जाती

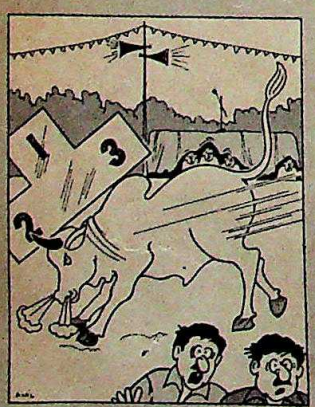

है कि वह अपना दिल तोड़ने के बजाय अगली बारी का इंतजार करे. लेकिन मामला तब बहुत पेचीदा हो जाता है जब प्रतियोगी एक सांड हो और वह भी अपने मालिक के लाड़-प्यार में ऐसा बिगड़ा हुआ कि न किसी की सुने और न किसी की माने. पिछले दिनों महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अकरा इलाके में आयोजित पशु मेले के दौरान ऐसे ही एक सांड ने वो करतब दिखाए कि आयोजकों की नाक में दम हो गया.

हर साल आयोजित किए जाने वाले इस पशु मेले में दूर-दूर के इलाकों से पशुओं को खरीद-फरोख्त के लिए लाया जाता है और इस अवसर पर उनकी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं. ऐसी ही एक प्रतियोगिता में जब सांडों को इनाम दिए जाने का समय आया तो वहां सज-संवरकर आए एक ऐसे सांड ने उत्पात मचा दिया जिसे इनाम की सूची में शामिल नहीं किया गया था. देखते ही देखते इस सांड ने वहां का ताम-झाम उखाड़ फेंका. आयोजकों की सिट्टीपिट्टी ऐसी गुम हुई कि बेचारों को मंच के नीचे छिपकर अपनी जान बचानी पड़ी. यह नाटक तब कहीं जाकर खत्म हुआ जब सांड के मालिक ने उसे पुचकारकर और दिलासा देकर शांत होने के लिए राजी किया.

हथियारबंद सुंदरी

■ जब से आतंकवाद का दौर शुरू हुआ है तब से अपने साथ स्टेन-गन से लैस कमांडो लेकर चलना तो सामाजिक रुतबे की बात बन चुकी है. ऐसे में यह सवाल उठना वाजिब ही है कि वे लोग क्या करें जो कमांडो रखने की हैसियत नहीं रखते—खासतौर से वे कामकाजी महिलाएं जिन्हें बसों और लोकल ट्रेनों में छेड़छाड़ करते 'छापामारों' से दो-चार होना पड़ता है?

इस सवाल का सटीक जवाब बंबई के एक तकनीकी संस्थान में काम करने वाली एक महिला अधिकारी ने पेश किया है. इन देवी जी ने अपने घर में कई सांप पाले हुए हैं जो न केवल किसी पालतू जानवर की तरह उनके साथ दोस्ती निभाते हैं बल्कि उनकी रक्षा की जिम्मेदारी भी पूरी करते हैं. हर सुबह दफ्तर के लिए घर से निकलने से पहले ये महोदया एक सांप अपने बैग में रख लेती हैं. योजना यह रहती है अगर बस या ट्रेन में कोई मनचला या उचक्का इन्हें तंग करना चाहे तो उससे निबटने का काम सांप के जिम्मे छोड़ दिया जाए. इनका कहना है कि ऐसे हालात में सांप से अच्छा और कोई हथियार नहीं हो सकता. अपनी इसी मान्यता को कानूनी जामा पहनाने के लिए पिछले दिनों इन देवी जी ने पुलिस विभाग से आवेदन किया है कि उन्हें यह

जीवित हथियार अपने पास रखने का लाइसेंस दिया जाए. बेचारे पुलिस अधिकारी तय नहीं कर पा रहे हैं कि आवेदन पर किस कानून के तहत फैसला किया जाए.

संकलन: **विजय क्रान्ति**

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विसंगतियां और विवाद

विवादों से ही शुरुआत हुई बीते पखवाड़े, और वास्तव में नए वर्ष की. निजी सैर-सपाटे को राजनैतिक रंग दिया गया, तो एक नेता की विरासत पर विवाद ने लोकतंत्र को जैसे हाशिये पर ला खड़ा किया. अपने इतालवी रिश्तेदारों और बच्चन परिवार के साथ लक्षद्वीप के बंगारम में छुट्टियां बिताकर राजीव गांधी ने जैसे अपने हाल के दावे को ही सिद्ध किया कि वे किसी आलोचना से विचलित नहीं होते. राजीव ने तो समुद्र में कूदकर व्हेल मछली की जान बचाई मगर उनके मित्र अमिताभ बच्चन सैर करके लौटते हुए कोचीन हवाई अड्डे पर इंडियन एक्सप्रेस के छायाकार से पीछा न छुड़ा पाए. और तो और, वे उससे निबटते हुए फोटो भी खिंचवा बैठे. और उधर सोनिया लाल स्वीमिंग सूट में समुद्र तट पर अलसाई पड़ी रहीं. रूसी शायद खुश हों रंग के इस चुनाव से.

राजीव कंजवन

राजीव गांधी छुट्टी मनाने लक्षद्वीप गए. इस निजी यात्रा को राजनैतिक रंग दिया गया

श्याम टेकवानी

जानकी रामचंद्रन अपने पति की विरासत की लड़ाई में अंततः विजयी हुईं और नई मुख्यमंत्री बनीं

एक महिला अगर सूर्य स्नान कर रही थीं तो दूसरी अपूरणीय क्षति के दुख से उबर कर सत्ता सूर्य की उपासना में लग गईं. जानकी रामचंद्रन पति की मृत्यु का दुख भुलाकर उनकी राजनैतिक विरासत को हथियाने के संघर्ष में जुट गईं. लेकिन द्रविड़ राजनीति पर, जिसकी नींव ही ब्राह्मण विरोध रही है, दबदबे की लड़ाई में दो ब्राह्मण स्त्रियां आमने-सामने थीं. यही विसंगति एक और रूप—लोकतंत्र पर हावी परिवारवाद—में एक और पार्टी में उजागर हुई. दिल्ली के नजदीक एक राजनैतिक कुल-पिता देवीलाल पुत्र-प्रेम और राजनैतिक नैतिकता के बीच सही संतुलन तलाशते रहे. लेकिन कामयाब नहीं हो सके, बावजूद इसके कि हरियाणा की राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है. नैतिकता की असुविधाजनक उलझन आंध्र प्रदेश में भी छाई रही. मुख्यमंत्री नंदमूरि तारक रामराव, जिनके खिलाफ राज्य के हाईकोर्ट की पांच सदस्यीय खंडपीठ को पद के दुरुपयोग का जाहिरा मामला नजर आया, न्यायपालिका पर जबाबी हमले करते रहे.

जबकि राजनीति में उथलपुथल जारी रही, शेयर बाजार के लाखों खिलाड़ियों के लिए वर्ष की शुरुआत सचमुच खुशखबरी से हुई. अखबारों में उद्योग-व्यापार संबंधी पन्नों की सुर्खियों ने उन्हें उत्साह से भर दिया. हताशा के एक पूरे वर्ष के—जिसमें कई बार शेयर बाजार की जमीन खिसकी—बाद तेजड़ियों की फिर बन आई. लेकिन यह उत्साह पेट्रोल पर प्रति लिटर एक रुपया बढ़ने से फीका पड़ गया.

भवान सिंह

मुख्यमंत्री देवीलाल अपने पुत्र-प्रेम और राजनैतिक नैतिकता में सही संतुलन तलाशते रहे

राजनैतिक हिंसा सरकार के लिए आर्थिक संकट से भी ज्यादा परेशानी का बायस है. यहां तक कि गृह मंत्रालय ने ज्यादा पुलिस बल की मांगों पर से रोक हटा ली. सीआरपी की नई टुकड़ियां दार्जिलिंग भेजी गईं जिन्हें एक नए दुश्मन से—गोरखा मुक्ति मोर्चा, जिस पर से उसके संस्थापक सुभाष घीसिंग की पकड़ तेजी से ढीली पड़ती जा रही है—उलझना पड़ा. इसके और पूरब मेघालय व त्रिपुरा में आसन्न विधानसभा चुनावों को लेकर जातीय तनाव में बढ़ोतरी के साथ अनिष्ट सूचक माहौल बनता रहा. उधर पंजाब प्रदेश इंका उपाध्यक्ष जगतराम और पूर्व मंत्री तरलोचन सिंह रियासती की हत्याओं से लगने लगा कि इंकाई राजनीतिक जैसे जोखिम में घिरी नस्ल के लोग हों.

श्याम टेकवानी

मेजर जनरल हरकीरत सिंह को जाफना से लौट आना पड़ा, आलाकमान की मर्जी पर

उम्मीदों और अनिश्चितताओं भरे पखवाड़े के खत्म होते-होते कम-से-कम दो अटकलों पर तो अंतिम फैसला हो ही गया. पिछले नवंबर में सोवियत प्रधानमंत्री के मोटर काफिले से भिड़ंत के बाद दिल्ली पुलिस आयुक्त वेद मारवाह के कैरियर को लेकर चल रही अटकलों पर अंततः राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड में उनके तबादले के साथ ही ब्रेक लग गया. 3000 किमी. दूर एक और वर्दीधारी व्यक्ति को तबादले से गुजरना पड़ा. जैसे ही जाफना में हुई लड़ाई का आकलन पूरा होने को आया, सैनिक नेतृत्व ने मेजर जनरल हरकीरत सिंह से भारतीय शांति सेना की बागडोर चुपचाप छीन ली. इन तबादलों की प्रक्रिया महीनों पहले शुरू हुई थी, लेकिन प्रतिकूल प्रचार की आशंका से उसे टाल दिया गया था. अब जबकि लोग भूल चुके हैं, उन्हें सजा देकर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि उसकी अपनी याददाश्त जनता की याददाश्त जितनी कमजोर नहीं है. —शेखर गुप्ता

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रधानमंत्री की छुट्टियां

निर्जन टापू पर निश्चिंत पड़ाव

आलोचनाओं के बावजूद राजीव परिवार और दोस्तों की पिकनिक मस्त रही

लगता है कि 1987 की तनाव भरी घटनाओं ने दुनिया के बड़े-बड़े राज-नेताओं के भी छक्के छुड़ा दिए. शायद यही कारण था कि साल खत्म होने पर मिखाइल गोर्बाचेव ने काला सागर तट की सैरगाह का रुख किया; रोनाल्ड रेगन ने सांता बारबरा में अपने लांच की शरण ली और भारत में राजीव गांधी ने भी अपने घरेलू लाव-लश्कर के साथ बंगारम की ओर कूच कर दिया. छुट्टियां मनाने के इस फैसले के पीछे उनका इरादा चमचों की भीड़, फाइलों, समस्याओं और असंतुष्टों से पीछा छुड़ाने के लिए ऐसे दूर और एकांत स्थान पर जा बैठना था जहां किसी तरह की चीख-पुकार न पहुंच सके. 36 टापुओं और 44 हजार आबादी वाले लक्ष-द्वीप में बंगारम टापू मात्र आधे वर्ग किलो-

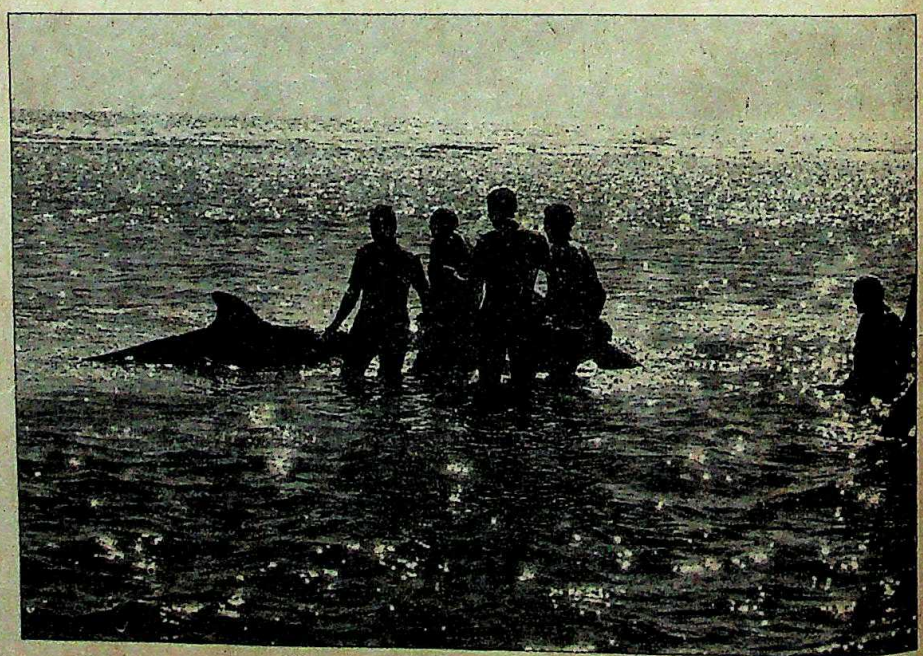

डॉल्फिन को बचाने के बाद राजीव; और (ऊपर) समुद्र से बाहर आते हुए

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मीटर क्षेत्र वाला ऐसा ही निर्जन स्थल है.

सामरिक दृष्टि से नाजुक माने जाने वाले लक्षद्वीप का यह इकलौता ऐसा टापू है जहां विदेशियों को जाने की छूट है और जहां नशाबंदी नहीं है. बाकी दुनिया से पूरी तरह कटा होने के कारण यह टापू पूरी तरह सुरक्षित माना जाता है. लक्षद्वीप के पुलिस प्रधान पी.एन. अग्रवाल कहते हैं, "यह प्राकृतिक कारणों से भी एक सुरक्षित स्थान है."

हालांकि सरकार की ओर से इस टापू तक किसी बाहरी आदमी को न पहुंचने देने के सभी संभव प्रयास किए गए थे पर इसके बावजूद यहां होने वाले कार्यकलापों के बारे में समाचार माध्यमों की रुचि को कम नहीं किया जा सका. यह टापू उत्सुकता का केंद्र 26 दिसंबर के दिन बना जब स्थानीय प्रशासन के नारंगी और सफेद रंग के हेलिकॉप्टर से राजीव के बेटे राहुल और उसके चार दोस्त उतरे. उनके बाद छुट्टी मनाने के लिए आने वाले दस्तों का सिलसिला बंध गया. पत्रकारों को यहां से दूर रखने के लिए सरकारी मशीनरी ने पूरा जोर लगा दिया.

टापू पर आमंत्रित मेहमानों की सूची ही अपने आप में गरमागरम खबरों का स्रोत रही. किस्मत वालों की इस सूची में राहुल और प्रियंका के चार दोस्त, सोनिया गांधी की बहन, जीजा और उनकी बेटी, सोनिया की विधवा माता आर. मायनो तथा भाई और मामा भी थे. इनके अलावा पूर्व सांसद अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और उनके तीनों बच्चे भी थे. बच्चन परिवार से आने वाले मेहमानों में 'फेरा' के तहत कथित हेराफेरी के लिए विवादास्पद अजिताभ

सभी फोटो: राजीव केलकर

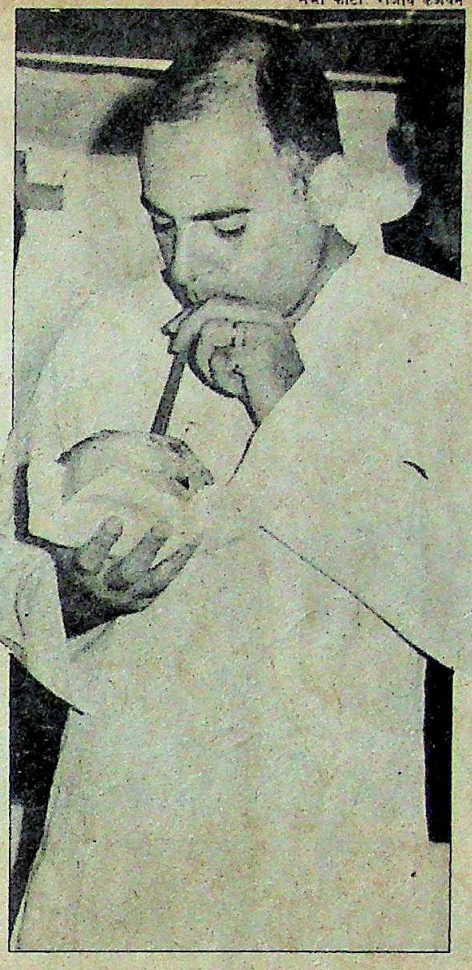

नारियल पानी की चुस्कियां: तनावों से दूर

बच्चन की बेटी भी थी. बाकी मेहमानों में केवल दो हिंदुस्तानी और थे—पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण सिंह के भाई बिजेंद्र सिंह और उनकी पत्नी. बाकी सभी विदेशी थे.

हालांकि राजीव और सोनिया ने अपनी छुट्टियों की शुरुआत 30 दिसंबर की दोपहर के बाद की पर अमिताभ को लेकर विशेष कोचीन-कवारात्ती उड़ान पर आया हेलिकॉप्टर इससे अगले दिन वहां पहुंचा. उनकी पत्नी जया अपने बच्चों और प्रियंका को लेकर चार दिन पहले ही वहां पहुंच गई थीं. इस रणनीति का लक्ष्य बंगारम में अमिताभ की मौजूदगी पर परदा डाले रखना था. लेकिन 31 दिसंबर के दिन यह भेद छिपाए न छिप सका क्योंकि हेलिकॉप्टर को बंगारम पहुंचने से पहले कवारात्ती टापू पर ईंधन लेने के लिए 50 मिनट के लिए रुकना पड़ा. बाद में जब वे वापसी के समय कोचीन हवाई अड्डे पर उतरे तो 'इंडियन एक्सप्रेस' के एक फोटोग्राफर ने उन्हें देख लिया और उसने अमिताभ की गुस्से भरी चेतावनियों के बावजूद उनके चार फोटो खींच लिए.

राजीव के इतालवी ससुराली रिश्तेदारों के अलावा बच्चन परिवार की मौजूदगी ने राजीव के आलोचकों को सबसे अधिक राजनैतिक बारूद उपलब्ध कराया. विरोधियों का एक सवाल यह था कि अजिताभ के परिवार के लोगों और उनके भाई के साथ रंगरेलियां मनाकर आखिर राजीव उन सरकारी अधिकारियों को क्या संकेत भेजने की कोशिश कर रहे हैं जो आजकल स्विट्जरलैंड में अजिताभ की संपत्ति की जांच कर रहे हैं. कवारात्ती में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के

बंगारम का विहंगम दृश्य (बाएं); और वह काटेज जहां गांधी दंपती ठहरा

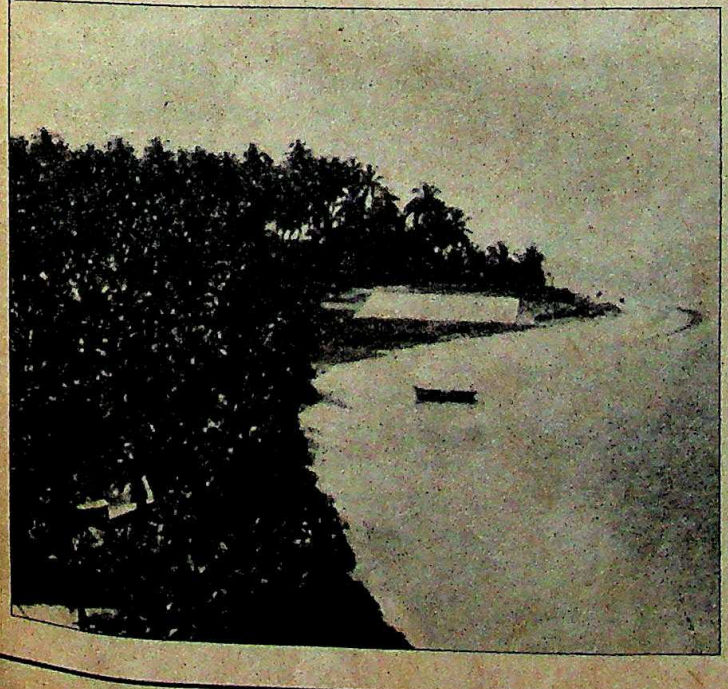

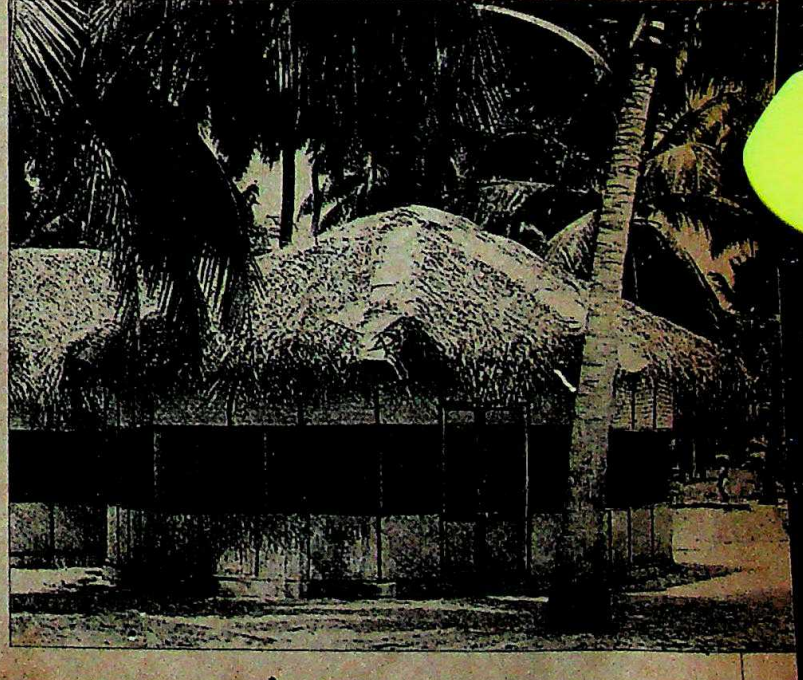

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

महासचिव कुंजी कोया का कहना था, "यह बहुत दुख की बात है कि हेलिकॉप्टर का इस्तेमाल केवल एक आदमी के लिए किया जाए और वह भी एक ऐसे शख्स के लिए जिसका नाम देश के सबसे बड़े स्कैंडल में उलझा हुआ है."

लेकिन छुट्टी मनाने वाले हफ्ता भर मस्त रहे. एक खूबसूरत और गैरआबाद टापू पर उनका पूरा कब्जा था. लिहाजा पूरा वक्त उन्होंने निश्चितता के साथ तैरने, धूप सेंकने, मछली पकड़ने और नौका चलाने में बिताया. इस मौज-मस्ती के दौरान यह दल पास ही के दो निर्जन टापुओं तिन्नाकारा और पराली पर पिकनिक मनाने भी गया. इसके अलावा बीच-पार्टियों, संगीत और मछली मार अभियानों की भी भरमार रही. जहां राजीव, राहुल और प्रियंका ने अपना काफी समय पानी में बिताया, वहां सोनिया ने दमे के कारण अपनी मां और जया के साथ शीशे की तली वाली नौका में समुद्र तट में फैली मूंगे की चट्टानों को निहारने का आनंद लूटा.

जीवन जोस/इंडियन एक्सप्रेस

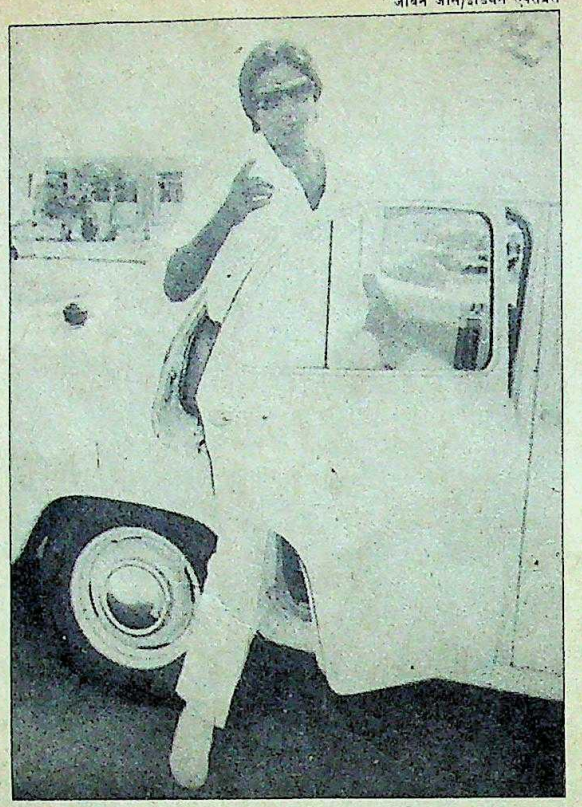

छायाकार को धमकाते अमिताभ

इस दौरान राजीव कई बार टापू पर इस तरह टहलने के लिए निकले मानो वे इस जगह से पूरी तरह वाकिफ हों. एक बार तो वे छिछले पानी में आ फंसी एक डॉल्फिन को बचाने के लिए पानी में कूद पड़े इससे पहले नवंबर 1985 में भी राजीव ने बंगारम में एक दिन बिताया था.

लेकिन इस बात का अनुमान लगा पाना बहुत कठिन है कि साल के अंत में हुए इस तमाशे पर कुल कितना खर्च आया कारण यह है कि कई एजेंसियों ने अपनी-अपनी तरह से इस पर खर्च उठाया. उदाहरण के लिए खाने की व्यवस्था मनोरंजन, पर्यटन और जल संबंधी खेलों के विकास संगठन 'स्पोर्ट्स' की ओर से की गई थी. यह लक्षद्वीप प्रशासन का एक विभाग है. छुट्टियों के दौरान इस संगठन के दो बावर्चियों समेत पांच कर्मचारी वहां मौजूद रहे. लेकिन भोजन के निर्धारण और पकाने का निरीक्षण दिल्ली से आए प्रधानमंत्री के निजी रसोइए ने किया.

दिल्ली से ही तरह-तरह की शराब मंगाई गई थी. इस मौके के लिए अगाट्टी में खासतौर से 100 मुर्गे-मुर्गियों का फार्म लगाया गया चीनी और ताजा मछली के अलावा पपीते, सपोटा, केले और अमरूद की व्यवस्था लक्षद्वीप से ही की गई थी. कवारात्ती से मक्खन और 100 डबल रोटियों की व्यवस्था की गई और कोचीन से चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक्स के 40 क्रेट, 300 बोतल मिनरल वाटर, अमूल मक्खन, काजू, खाने की दूसरी चीजें, 20 किलो आटा, 105 किलो बासमती चावल और ताजा सब्जियां कोचीन से लाई गईं.

'स्पोर्ट्स' के अधिकारियों का कहना है कि प्रशासन ने सभी बिल मंगवाए हैं ताकि राजीव इनका भुगतान कर सकें. लक्षद्वीप के कलेक्टर के.के. शर्मा का कहना था, "हमने वीआईपी लोगों की छुट्टियों के लिए किसी तरह की विशेष व्यवस्था नहीं की है." और हबीबुल्ला की सफाई थी, "मेरा काम तो प्रधानमंत्री को बस बंगारम पहुंचाना भर था."

लेकिन इन सब दावों के बावजूद वहां की गई फिजूलखर्ची साफ दिखाई दे रही थी. देश के सबसे प्रमुख युद्धपोत 'आईएनएस विराट' का इस्तेमाल राजीव गांधी के परिवार की सवारी के तौर पर किया गया और इस दौरान यह 10 दिन तक अरब सागर में ही घूमता रहा. इस युद्धपोत पर होने वाला दैनिक खर्च बेहिसाब है क्योंकि यह जहां भी जाता है इसके साथ सुरक्षा पोतों का पूरा काफिला चलता है. बताया जाता है कि इस काम के लिए वहां एक पनडुब्बी भी तैनात की गई थी. इसके अलावा अगाट्टी में विशेष उपग्रह संचार संपर्क की व्यवस्था भी की गई.

बहरहाल, लक्षद्वीप को जमकर प्रचार मिला है. स्थानीय प्रशासन को उम्मीद है कि इस कारण अब यहां पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि होगी. यह असर दिखने भी लगा है. उदाहरण के लिए कोचीन में लक्षद्वीप के पर्यटक कार्यालय का कहना था कि 8 जनवरी के दिन सामान्य से पांच गुना लोगों ने जानकारी मांगी.

6 जनवरी के दिन जब यह पिकनिक खत्म हुई तब वहां से सबसे पहले प्रियंका और उसके साथी गोवा के लिए निकले. उनके बाद बुजुर्ग विदेशी लोग रवाना हुए और फिर अमिताभ और उनका परिवार. उसी दिन दोपहर 1.20 बजे राजीव ने राहुल के साथ हेलिकॉप्टर में प्रस्थान किया. अमीनो में 1988 को अपने सबसे पहले कार्यक्रम में भाग लेने से पहले राजीव ने राहुल को आईएनएस विराट पर उतारा ताकि वह बाद में अपने पिता के साथ मंगलूर तक की यात्रा कर सके. आखिर में सोनिया अपने रिश्तेदारों के साथ मुस्कराते हुए रवाना हुईं. लेकिन यह मुस्कराहट कोचीन पहुंचते ही गायब हो गई.

लेकिन इसके ठीक विपरीत नौसैनिक हेलिकॉप्टर से उतरते समय राजीव प्रसन्न-चित्त दिखाई दे रहे थे. 6 जनवरी के दिन अमीनी द्वीप में अपनी जनसभा में उन्होंने कहा कि "बहुत शानदार छुट्टियां थीं." बाद में उन्होंने भूक्षरण और विकास कार्यक्रमों का मुआयना किया. इस दौरान उनके साथ छुट्टियों का जो एक स्मृति चिन्ह था वह एक वाटरप्रूफ घड़ी थी जिसे वे नौका चलाने और गोताखोरी के दौरान पहनते आ रहे थे.

—अनीता प्रताप, लक्षद्वीप में

राजीव की वापसी: भावभीनी विदाई

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गोपी अरोड़ा

चौकड़ी से बाहर

साजिश से, या नई जवाबदेही

प्रधानमंत्री सचिवालय से उनकी विदाई की अटकलें करीब छह माह से लगाई जा रही थीं. लेकिन यह उम्मीद नहीं थी कि वामपंथी रुझान वाले, प्रधानमंत्री के विशेष सचिव गोपी कृष्ण अरोड़ा को सूचना और प्रसारण मंत्रालय का सचिव बना दिया जाएगा. वैसे, वरिष्ठ अफसरशाहों को यह पद कतई रास नहीं आता.

बहरहाल, उनके इस तबादले के बाद राजीव गांधी के सलाहकार के रूप में अरोड़ा की भूमिका के बारे में तरह-तरह की अफवाहें फैलने लगीं. अरोड़ा तो चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि वे कुछ इंका नेताओं तथा कुछ अफसरशाहों की साजिशों के शिकार हुए हैं. पिछले कुछ महीनों से आरोप लगाया जा रहा था कि अरोड़ा राजनैतिक, आर्थिक और रक्षा संबंधी नाजुक मामलों में राजीव गांधी को उपयुक्त सलाह नहीं दे पा रहे थे. अरोड़ा उत्तर प्रदेश के 1957 के बैच के आईएएस अधिकारी हैं.

वरिष्ठ अधिकारी और महत्वपूर्ण पद पर होने के कारण अरोड़ा सिर्फ आर्थिक मुद्दों और सरकारी नियुक्तियों का ही काम नहीं बल्कि गुप्तचर संस्थाओं का भी काम देखते थे, हालांकि इस काम से उन्हें हाल ही में मुक्त कर दिया गया था. उनके अधिकारों का दायरा इतना विस्तृत था कि प्रधानमंत्री कार्यालय में होने वाली कुछ ही बैठकें ऐसी होंगी जिनमें वे उपस्थित नहीं रहे होंगे. प्रधानमंत्री प्रायः सभी मामलों पर उनकी राय लेते थे. एक सचिव ने कहा, "हमें यह समझा दिया गया था कि गोपी अरोड़ा के मुंह से निकला हर शब्द प्रधानमंत्री का आदेश है." अपनी इसी गड़बड़ छवि के कारण अंततः उन्हें यह पद गंवाना पड़ा.

यह भी सही है कि प्रधानमंत्री की सचिव सरला ग्रेवाल आमादा थीं कि प्रधानमंत्री सचिवालय में अफसरशाही की शक्ति का केंद्र एक ही रहे. और वास्तव में अपना कार्यकाल दूसरी बार बढ़ाए जाने के बाद ही उन्होंने एक परिपत्र जारी किया था कि सभी फाइलें उनके पास से होकर ऊपर जाएंगी. यह निर्देश पिछले ही महीने लागू हुआ. असल में ग्रेवाल का कार्यकाल बढ़ाए जाने से ही इस बात का संकेत मिल गया था कि प्रधानमंत्री कार्यालय में अरोड़ा के दिन पूरे हो रहे हैं.

अरोड़ा के दबदबे से कई अफसरशाह दुखी थे. यहां तक कि सरकारी सचिवों की नियुक्तियों में भी उनकी दखलंदाजी होती थी. पिछले साल ही उन्हें केंद्र में छह आईएएस अधिकारियों को पीछे छोड़कर तरक्की दी गई और सचिव बनाया गया था. पीछे छूटे अफसरों ने ऊंची नियुक्तियों में राजीव के गलत रवैये के लिए अरोड़ा को ही दोषी ठहराया. कुछ वरिष्ठ मंत्री तथा सांसदों ने भी सरकारी उपक्रमों के ऊंचे पदों पर कार्यकुशल अफसरों की नियुक्ति में बाधा डालने का

प्रमोद पुष्करणा

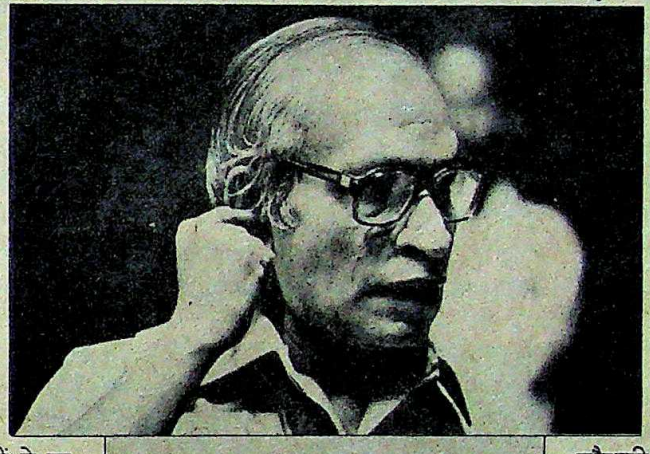

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि गोपी अरोड़ा कुछ इंका नेताओं और अफसरशाहों की साजिशों के शिकार हुए हैं

आरोप भी अरोड़ा पर लगाना शुरू कर दिया था. और हालांकि विश्वनाथ प्रताप सिंह के निकाले जाने या बोफोर्स सौदे से अरोड़ा का कोई लेना-देना नहीं था, फिर भी विरोधी प्रचारों के कारण अंततः उन्हें ही बलि का बकरा बनना पड़ा.

उनके तबादले के संबंध में जो दूसरे कारण गिनाए जा रहे हैं उनमें एक है समाजवाद तथा सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका के बारे में राजीव का बदला हुआ रुख. इसके सबूत के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के खिलाफ राजीव गांधी के हाल के दनादन दिए गए बयानों को गिनाया जा रहा है.

लेकिन तबादले का सबसे युक्तिसंगत कारण यह नजर आता है कि राजीव अब सिद्ध करना चाहते हैं कि वे सलाहकारों के बिना भी काम चला सकते हैं. तीन वर्षों के शासन में वे अपने दफ्तर साउथ ब्लॉक और पार्टी में उभरते सत्ता केंद्रों को एक-एक करके कुचलते रहे हैं.

31 दिसंबर 1984 को सत्ता में आने के तुरंत बाद ही उन्होंने 23 वर्षों से प्रधानमंत्री कार्यालय में जमे आर.के. धवन को दरवाजे की राह दिखा दी. अगले दो वर्षों तक वे कई सलाहकारों को आजमाते रहे. इनमें संसदीय सचिव, दोस्त, और ममेरे भाई अरुण नेहरू तक शामिल हुए. जब भी लोगों ने किसी को उनका पक्का विश्वासपात्र समझना शुरू किया, उसके पर कतर दिए गए. 1986 के में राजीव के करीबी लोगों में संचारमंत्री अर्जुन सिंह, योजनामंत्री पी. शिवशंकर और पूर्व वित्तमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का नाम लिया जाता था. इन सभी को बारी-बारी से उनकी औकात जता दी गई. प्रधानमंत्री निवास में काफी दखल रखने वाले माखनलाल फोतेदार को भी 1987 के मध्य में हटाकर मंत्रिमंडल में बिठा दिया गया.

अरोड़ा ही अब तक बचे हुए थे. अब प्रधानमंत्री सचिवालय से उनके निष्कासन से सत्ता का वह पुराना ढांचा ढह गया है, जिसमें फैसले यह चौकड़ी करती थी और बाद में मंजूरी राजीव देते थे. कैबिनेट स्तर के एक वरिष्ठ मंत्री ने स्वीकार किया कि "यह महज पत्र-पत्रिकाओं द्वारा बनाया गया मिथक है कि दून स्कूल के मित्र और कुछ विशिष्ट नेता राजीव के फैसलों पर हावी हैं."

हालांकि अरोड़ा अब सत्ता केंद्र मानी जाने वाली जमात से बाहर हो गए हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें समाप्त नहीं हुई हैं. आलोचकों का कहना है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय का सचिव होने के नाते अब उनका सिर हमेशा ही ओखली में रहेगा, क्योंकि सरकारी प्रचार माध्यमों—विशेषकर दूरदर्शन—की हर गलती के लिए उन्हीं को जिम्मेदार ठहराया जाएगा.

लोग यह भी तर्क देते हैं कि अरोड़ा का तबादला दिसंबर 1989 में होने वाले आम चुनावों के मद्देनजर सरकार की छवि सुधारने की नीति का एक हिस्सा है. राजीव पहले ही इंडियन एक्सप्रेस के पूर्व संपादक और अपने दून स्कूल सखा सुमन दुबे को मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव पद सौंप चुके हैं. कुछ समय में छवि सुधार की कोशिशें सामने आएंगी. दोनों की जोड़ी उनके मकसद पूरे नहीं कर पाती तो संभव है राजीव फिर कोई उलटफेर करें.

—प्रभु चावला

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हरियाणा

इस्तीफों की राजनीति

देवीलाल में निष्ठा जताने के लिए मंत्रिमंडल का इस्तीफा

सत्ता में आने के बाद से ही हरियाणा के मुख्यमंत्री देवीलाल पर भाई-भतीजावाद चलाने के आरोप लगते रहे हैं. इन आरोपों के बावजूद लोकदल (ब) के भीतर देवीलाल के बेटों के दबदबे में हाल तक कोई कमी नहीं आई थी. लेकिन पिछले पखवाड़े उनके दो बेटों के अप्रत्याशित इस्तीफों का जैसे नाटकीय असर हुआ. हरियाणा के पूरे मंत्रिमंडल ने भी इस्तीफा दे दिया, यह जताने के लिए कि उनकी आस्था देवीलाल में ही है, उनके बेटों में नहीं.

इस राजनैतिक संकट की शुरुआत 28 दिसंबर को हुई जब देवीलाल ने घोषणा की कि उनके दो बेटों— प्रदेश लोकदल (ब) अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य ओमप्रकाश चौटाला और विधायक रणजीत सिंह—ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है. ऐसा उन आरोपों को शांत करने के लिए किया गया कि वे दोनों प्रशासनिक कामों में हस्तक्षेप करते रहे हैं और पार्टी के भीतर गुटबंदी को बढ़ावा देते रहे हैं.

शुरू में मुख्यमंत्री ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से ओमप्रकाश के इस्तीफे को लोकदल (ब) अध्यक्ष हेमवतीनंदन बहुगुणा और रणजीत सिंह का इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष हरमिंदर सिंह चाथा के पास भेज दिया. बाद में ओमप्रकाश ने राज्यसभा से और रणजीत ने आवास और नगर विकास प्राधिकरण (हुडा) के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा देने की पेशकश की. अफवाहों को समाप्त करने के लिए दोनों भाइयों ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन किया और घोषणा की, "हरियाणा में पार्टी और सरकार के एक ही मुखिया हैं, और वे हैं चौधरी देवीलाल."

पर इससे शांत होने के बजाय दूसरा विवाद ही छिड़ गया. जब देवीलाल ने इन लोगों के इस्तीफे ऊपर भेज दिए तो ओमप्रकाश द्वारा नियुक्त सिरसा, जींद, कुरुक्षेत्र और भिवानी जिलों के ढेर सारे पार्टी पदाधिकारियों ने भी इस्तीफे दे दिए. इन लोगों ने मांग की कि राज्यसभा से ओमप्रकाश के इस्तीफे को मुख्यमंत्री ऊपर न भेजें. पार्टी के अन्य लोगों ने रणजीत के पक्ष में तर्क दिए कि ओमप्रकाश भले अप्रत्यक्ष चुनाव से राज्यसभा में गए हों, रणजीत तो प्रत्यक्ष चुनाव से विधायक बने.

लेकिन मामला यहीं समाप्त नहीं हुआ. इन दोनों भाइयों की छवि 'शहीद' वाली बनती जा रही थी सो देवीलाल के सभी 28 मंत्रियों और संसदीय सचिवों ने 7 जनवरी को अपने इस्तीफे दे दिए.

देवीलाल और उनके मंत्री: निष्ठा का प्रश्न

प्रचारित तो यह किया गया है कि सभी ने अपनेआप इस्तीफे दिए हैं, पर असलियत शायद यही है कि देवीलाल उनके इस्तीफे चाहते थे ताकि उन्हें अंदाज लग जाए कि उनके मंत्रियों की असल में निष्ठा किसके प्रति है. जाहिर है मंत्रिमंडल में गुटबंदी इस हद तक बढ़ गई थी. सरकार में सहयोगी भारतीय जनता पार्टी को देवीलाल के हाथ में पूरा नियंत्रण आने से खुशी ही हुई.

भाजपा के अंदरूनी लोगों को लगता है कि मुख्यमंत्री के बेटों ने उनकी सत्ता को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था और राजनैतिक उत्तराधिकार की लड़ाई से तख्तापलट की पूरी तैयारी भी कर ली थी. दोनों भाइयों की तकरार पिछले पांच महीनों से काफी बढ़ गई थी खासकर तब से, जब से देवीलाल की तबीयत गड़बड़ रहने लगी है.

इन दोनों बेटों के राजनैतिक मंच से हटने से उन अधिकारियों और मंत्रियों ने राहत की सांस ली जो इनके दबाव से परेशान हो गए थे. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार दो खेमों में बंट गई थी. ओमप्रकाश गुट में राज्य के उप-मुख्यमंत्री बनारसीदास गुप्त, लोकदल (ब) के अधिकांश पदाधिकारी, कुछ मंत्री और अधिकांश सरकारी निगमों के अध्यक्ष थे. रणजीत के समर्थकों में उद्योगमंत्री संपत सिंह समेत दर्जन भर मंत्री और कई बड़े अधिकारी थे.

देवीलाल के नजदीकी लोग बताते हैं कि अगर बेटों की करतूतें हद से ज्यादा नहीं बढ़ गई होतीं तो वे उनसे इस्तीफा नहीं लेते. सिरसा में पार्टी के स्थानीय नेताओं ने कई बार देखा था कि तबादले जैसे अदने-से मुद्दे पर बड़े नेता किस तरह आपस में उलझ जाते थे. सितंबर में 'हुडा' ने भूमि विकास शुल्क कम करने का जो फैसला किया उसमें ये दोनों खेमे शामिल थे और इससे कॉलोनाइजरों को 30 करोड़ रुपए का मुनाफा हो गया.

बेटों पर आरोपों की बौछारों का सीधा असर देवीलाल की छवि पर पड़ रहा था. पार्टी में भी उनकी आलोचना होने लगी. प्रशासनिक हस्तक्षेपों से भी अधिक बुरा असर वित्तीय धांधलियों में उनके शामिल होने की चर्चाओं का पड़ा. और इससे भी बुरी बात यह थी कि दोनों गुट एक-दूसरे की गतिविधियों

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

देवीलाल के बेटों के बीच राजनैतिक उत्तराधिकार पाने का झगड़ा इतना बढ़ गया था कि पूरा राज्य मंत्रिमंडल ही इस कारण विभाजित हो गया

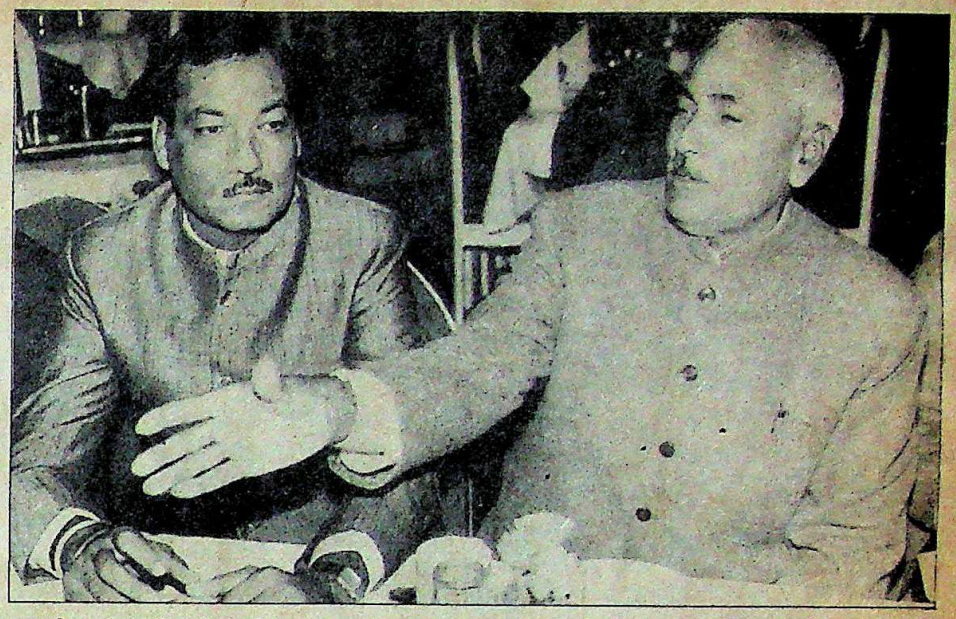

रणजीत (बाएं) और चौटाला: वनवास

की सूचनाएं इंका को पहुंचा रहे थे.

इस बात की संभावना नहीं है कि ये दोनों भाई अधिक दिनों तक राजनैतिक वनवास में रह पाएंगे. रणजीत सिंह ने कहा, "मैंने सिर्फ अपने पिता की छवि बचाने के लिए इस्तीफा दिया है." साथ ही उन्होंने जोड़ा, "वैसे मैं पूर्णकालिक राजनैतिक कार्यकर्ता हूं." उनके बड़े भाई ओमप्रकाश ने कहा, "मैं अपना इस्तीफा वापस नहीं लूंगा पर मैं चुनाव लड़कर पार्टी प्रमुख बनूंगा." और अभी तक देवीलाल जिस तरह अपने परिवार का पृष्ठपोषण करते रहे हैं उससे तो यही लगता है कि अगर दोनों बेटे पार्टी को खुलेआम दो गुटों में बांटने का काम नहीं करते तो देवीलाल भी उनकी वापसी में मदद करेंगे.

देवीलाल की कार्यशैली में सामूहिक इस्तीफों को असामान्य नहीं कहा जा सकता. मई 1978 में उन्होंने अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ इस्तीफा दिया था. और राज्यपाल द्वारा इसकी मंजूरी के कुछ ही घंटे बाद उसी दिन शाम को फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. इस बार एक बात उनके हक में है कि सभी मंत्रियों के इस्तीफा देने से उन्हें मंत्रिमंडल के पुनर्गठन का मौका हाथ लग गया है.

—विपुल मुद्गल

देवीलाल

'खुद इस्तीफे दिए'

इस्तीफों के मुद्दे पर पार्टी के बड़े नेताओं से बात करने के लिए देवीलाल दिल्ली जाने को तैयार थे और करीब दर्जन भर पूर्व मंत्री उन्हें घेरे खड़े थे. अफरातफरी के बावजूद उन्होंने वरिष्ठ संवाददाता ***विपुल मुद्गल*** *से बातचीत की. उसके अंश:*

● ***आपने बेटों से इस्तीफा क्यों लिया?***

मैंने किसी से इस्तीफा देने को नहीं कहा. मुझ पर लगाए जा रहे आरोपों को समाप्त करने के लिए उन्होंने खुद इस्तीफे दिए.

● ***पर आपके बेटों ने कहा है कि "पिता जी की इच्छाओं के आगे कुर्सी वगैरह हमारे लिए कतई महत्वपूर्ण नहीं."***

मैंने उन्हें सिर्फ अखबारों में छपी खबरें दिखाई थीं. मुझ पर उनके साथ पक्षपात करने के आरोप भी थे. इसलिए मैंने उनसे इस मुद्दे पर विचार करने और कुछ करने को कहा.

● ***आपके मंत्री भी मानते हैं कि सरकार में गुटबंदी थी.***

किस परिवार में मतभेद नहीं रहते? लेकिन हमारे बीच गंभीर राजनैतिक मतभेद का सवाल ही नहीं उठता. वे समझदार राजनीतिक हैं, और वे एक-दूसरे से प्रेम करते हैं.

● ***क्या यह सही नहीं है कि आपके कई रिश्तेदार बड़े पदों पर हैं?***

मेरे सिर्फ तीन रिश्तेदार— मोहिंदर सिंह (कृषि विपणन बोर्ड), टेकराम (आवास बोर्ड) और मेरा बेटा प्रताप सिंह (लघु उद्योग और निर्यात निगम)— अध्यक्ष हैं.

● ***मंत्रियों ने क्यों इस्तीफे दिए?***

देखिए, मंत्री सारी दुनिया को बताना चाहते थे कि वे ओमप्रकाश या रणजीत के साथ न होकर देवीलाल के साथ हैं.

● ***यानी दो खेमे बन गए हैं?***

नहीं. मैं सिर्फ आरोपों की बात कर रहा था. पार्टी एक थी और एक रहेगी. असलियत यह है कि कुछ हताश कांग्रेसी हमारे साथ गंदा खेल खेल रहे हैं.

● ***आप ऐसे कुछ कांग्रेसियों के नाम बताएंगे?***

असल में वे सब मेरे पीछे पड़े हैं. मगर आप जोर देते हैं तो मैं दो नाम लेता हूं—प्रदेश इंका अध्यक्ष बलबीर पाल शाह और केंद्रीय पर्यावरणमंत्री भजनलाल.

● ***लेकिन क्या भूमि विकास कर कम करने के फैसले से कॉलोनाइजरों को लाभ नहीं हुआ?***

असलियत यह है कि कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने उद्योग और नगर नियोजन मंत्री संपत सिंह के साथ फरेब किया. उन्होंने एक फाइल उनसे छिपा ली. भजनलाल के समय विकास शुल्क प्रति एकड़ 1.41 लाख रुपए था. बंसीलाल ने इसे बढ़ाकर 2.92 लाख कर दिया. अधिकारियों ने यह फाइल दबा दी और मेरी सरकार ने यह शुल्क 2.42 लाख प्रति एकड तय कर दिया. जब हमें इस घोटाले का पता चला तो हमने शुल्क 3.72 लाख रुपए प्रति एकड़ कर दिया. फाइल दबाने वाले दोनों आईएएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया.

● ***क्या आपके बेटों ने राजनीति से संन्यास ले लिया है?***

मेरा परिवार राजनीति से नाता कैसे तोड़ सकता है? मेरे परिवार की तीन पीढ़ियों के लोगों ने विभिन्न स्तर के 26 चुनाव लड़े. मोतीलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक के नेहरू परिवार के लोगों ने तो सिर्फ 16 चुनाव लड़े हैं.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कर्नाटक

दरक रहा मजबूत किला

आर्थिक संकट, दलगत भ्रष्टाचार और असंतुष्टों का जोर बढ़ा

1983 में जब जनता पार्टी कर्नाटक में सत्तासीन हुई थी तो लोगों में उत्साह और आशंका की मिली-जुली प्रतिक्रिया थी. आशंका यह थी कि केंद्र में बुरी तरह विफल होने के बाद यह दूसरा प्रयोग क्या कर्नाटक में सफल हो पाएगा. यह प्रयोग निश्चय ही सफल रहा. लेकिन अब हेगड़े के सुदृढ़ क़िले में दरारें दिखने लगी हैं. विरोधी दलों के इस दक्षिणी गढ़ में जनता शासन के पांच वर्षों का लेखा-जोखा प्रमुख संवाददाता अनीता प्रताप के द्वारा:

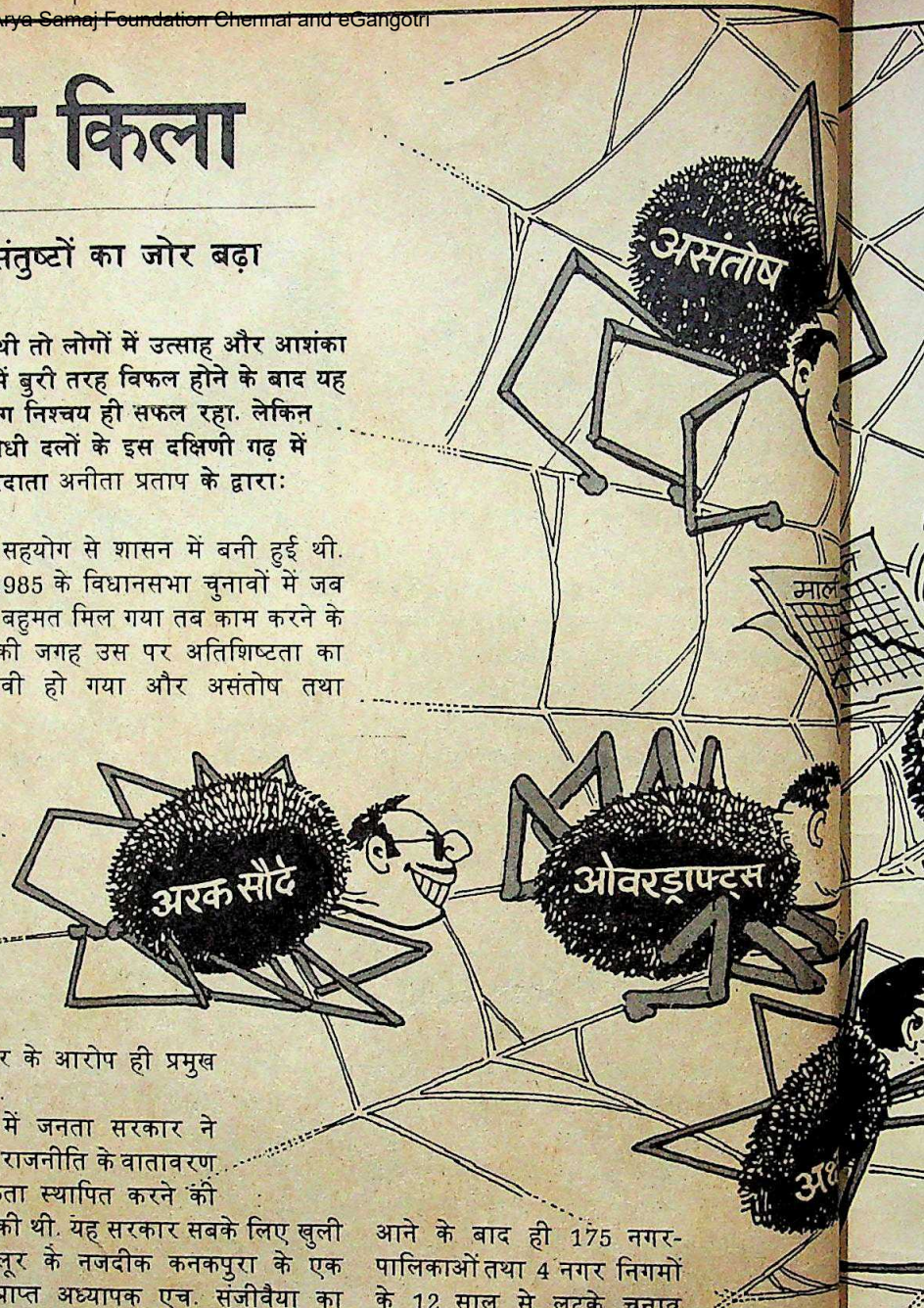

कर्नाटक में शासन के पांच साल पूरे करने के बाद मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े को महसूस हो रहा है कि विशाल जनसमर्थन को अब शर्तिया मानकर नहीं चला जा सकता. वे अब तक इसी जनसमर्थन के बल पर सरकार गिराने के प्रयास नाकाम करते रहे हैं और विरोधी अदालती फैसलों के बावजूद सत्ता में बने रह सके हैं.

अब यह मानना भी कठिन होता जा रहा है कि जनता की नजर में हेगड़े की छवि कभी ऐसे व्यक्ति की थी जो गलती कर ही नही सकता. अब उन पर एक साथ कई आरोप लगाए जा रहे हैं. जैसे— उनके शासन में राज्य की आर्थिक हालत खराब हुई है, वे असंतुष्टों से निबटने में निहायत कमजोर साबित हुए हैं. और उन पर निकम्मेपन, भ्रष्टाचार रोकने में नाकाम रहने तथा ऊंची जातियों की पकड़ कमजोर करने में असफल रहने का भी आरोप है. यह भी कहा जा रहा है कि उन्होंने राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरने की अपनी आकांक्षा के चलते राज्य के प्रति अपने कर्तव्य की अवहेलना की.

गुंडूराव की निष्ठुर तथा भ्रष्ट सरकार के खिलाफ जनाक्रोश के बल पर 1983 में जब जनता पार्टी ने शासन संभाला था तो उसमें प्रशासन को भ्रष्टाचार-मुक्त करने का संकल्प था. हेगड़े की समझदारी तथा जनसंपर्क के प्रति उनके रुझान से निश्चित रूप से इन उद्देश्यों को पाने में मदद मिली. कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री, 86 वर्षीय एस. निजलिंगप्पा कहते हैं, "जनता पार्टी की सरकार सिर्फ हेगड़े के कारण ही टिकी है. वे बुद्धिमान तथा दूरदर्शी हैं. वे सही स्थिति को भांपना तथा तमाम विरोधों और दबावों से जूझना भी भलीभांति जानते हैं."

संयोगवश वहां विकास की दिशा में बड़े प्रयास जनता शासनकाल के पहले दौर (1983-85) में ही किए गए. उस समय जनता सरकार अल्पमत में थी तथा दूसरे दलों के सहयोग से शासन में बनी हुई थी. लेकिन 1985 के विधानसभा चुनावों में जब उसे पूर्ण बहुमत मिल गया तब काम करने के उत्साह की जगह उस पर अतिशिष्टता का भाव हावी हो गया और असंतोष तथा भ्रष्टाचार के आरोप ही प्रमुख होने लगे.

शुरू में जनता सरकार ने अनैतिक राजनीति के वातावरण में नैतिकता स्थापित करने की कोशिश की थी. यह सरकार सबके लिए खुली थी. बंगलूर के नजदीक कनकपुरा के एक अवकाशप्राप्त अध्यापक एच. संजीवैया का कहना है, "अब हमें अधिकारियों की चिरौरी करने की जरूरत नहीं पड़ती. हम सीधे मंत्रियों के पास जा सकते हैं." गुंडूराव के शासन के उलट हेगड़े की सरकार जनता के प्रति जवाबदेह थी. मसलन आलोचनाओं के कारण उसने कई कदम वापस भी लिए.

उस समय सरकार ने कई नए कदम भी उठाए. जैसे सरकार की सहायता के लिए आर्थिक और योजना काउंसिल का गठन किया गया. इस काउंसिल के विशेषज्ञों ने सरकार की विकेंद्रीकरण की नीति, कृषि और औद्योगिक योजना बनाने तथा बिजली उत्पादन के लिए लंबी अवधि की योजनाएं बनाने में सरकार की मदद की. विकेंद्रीकरण को लागू करने में सरकार ने पूर्ण संकल्प का परिचय दिया. 1983 में पार्टी ने शासन में आने के बाद ही 175 नगर-पालिकाओं तथा 4 नगर निगमों के 12 साल से लटके चुनाव कराए और पार्टी के भीतर तथा बाहर विरोधों के बावजूद जनवरी 1987 में 20 जिला परिषदों तथा 2,536 मंडल पंचायतों के चुनाव कराए गए. राज्य जनता पार्टी के अध्यक्ष एम.पी. प्रकाश का कहना है, "लोक-तांत्रिक विकेंद्रीकरण जनता सरकार की प्रमुख उपलब्धि है." यह सच भी है.

सरकार ने किसानों पर कर घटाने के कई उपाय किए. इससे किसान आंदोलनों को दबाने में सहायता मिली. इसीलिए किसान लॉबी के पिछले दिसंबर में 'कन्नड़ देशम' नाम की क्षेत्रीय पार्टी बनाने की कोशिशों को ज्यादा सफलता नहीं मिली. ग्रामीण विकास की प्रधानता को पीने के पानी के लिए अपनाई गई व्यापक योजनाओं से भी जाना जा सकता है. सिर्फ दो साल में ही 76.6

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

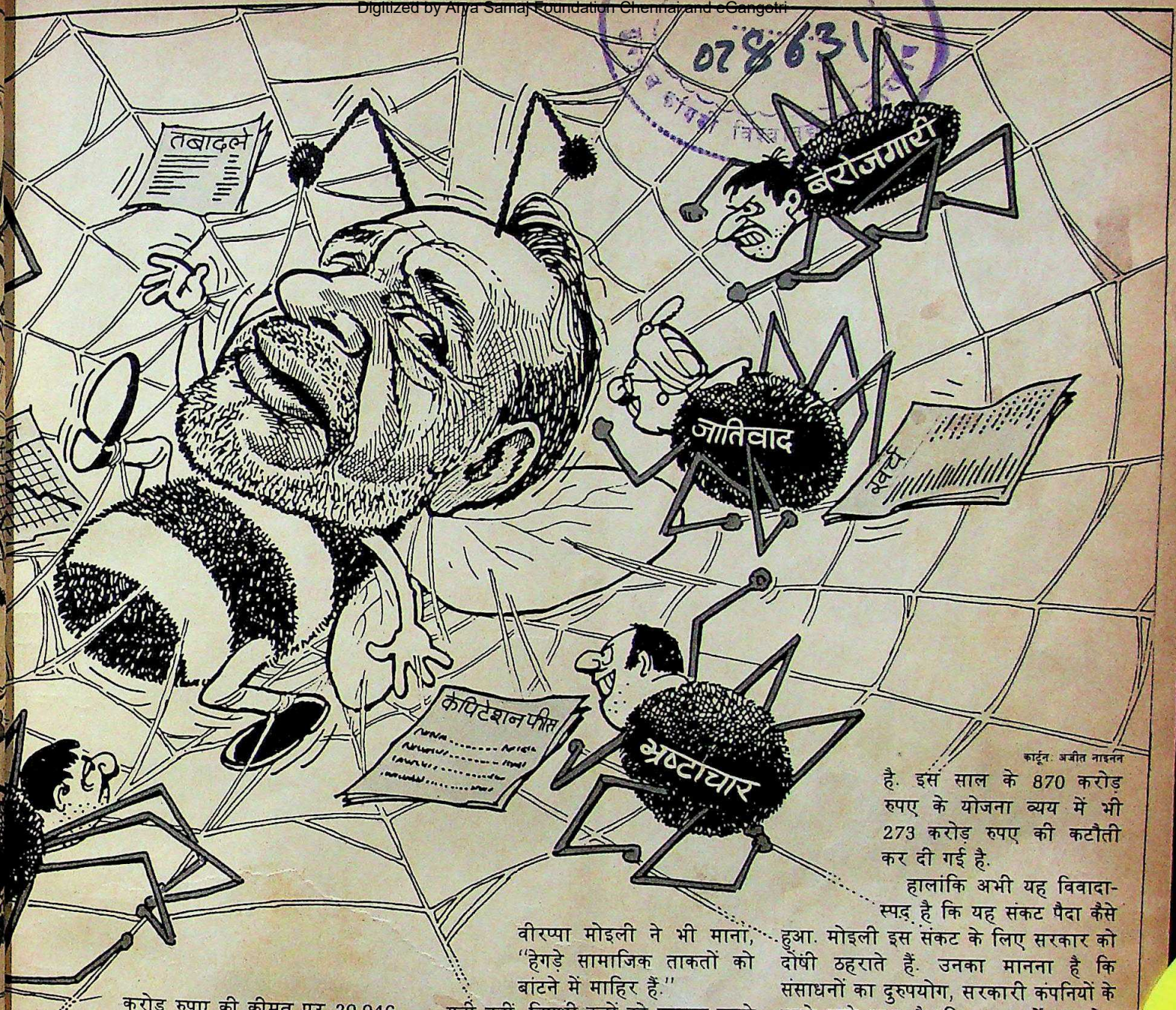

कार्टून: अजीत नाइनन

करोड़ रुपए की कीमत पर 29,046 ट्यूबवेल लगाए गए. इस अवधि में कुल 24,948 गांवों तक बिजली पहुंचाई गई.

लेकिन सबसे नाटकीय उपलब्धि तो इसने राजनैतिक क्षेत्र में प्राप्त की. सरकार दलबदल तथा राजनैतिक नेताओं की खरीद-फरोख्त के खिलाफ जनभावना बनाने में पूरी तरह सफल रही है. सरकार गिराने के इंका के प्रयास का तुरत भंडाफोड़ कर दिया गया.

राज्य में अपने विरोधियों से निबटने में हेगड़े की जेहाद छेड़ने वाली साफ-सुथरी छवि भी काम आई. बड़ी आसानी से वे फिल्म अभिनेता राजकुमार, किसान नेता नानजुंदास्वामी और बंगरप्पा तथा ए.के. सुबैया जैसे इंकाई अखाड़ेबाजों के पर कतरने में सफल रहे. इंकाई नेता तथा पूर्व वित्तमंत्री वीरप्पा मोइली ने भी माना, "हेगड़े सामाजिक ताकतों को बांटने में माहिर हैं."

यही नहीं, विपक्षी दलों को एकजुट करने के साथ ही मुख्यमंत्री ने केंद्र तथा राज्य के बीच राजनैतिक और आर्थिक संबंधों के मामले को भी तूल दिया. इस दौरान राज्य प्रशासन में कन्नड़ भाषा का प्रयोग 90 प्रतिशत तक बढ़ गया. पंचायत चुनावों में मतदान की आयु सीमा 18 वर्ष तक घटा दी गई तथा पंचायत में महिलाओं को 25 प्रतिशत आरक्षण दे दिया गया.

लेकिन जनता शासन के दूसरे दौर में सरकार आर्थिक मोर्चे पर ही सबसे ज्यादा असफल रही है. और यही असफलता इंका के लिए ईंधन का काम करेगी. 1981-82 के 2.22 करोड़ रुपए की बचत की तुलना में इस साल का अनुमानित घाटा 147.95 करोड़ रुपए है. हेगड़े खुद भी स्वीकार करते हैं कि 'निश्चित रूप से स्थिति अच्छी' नहीं है. इस साल के 870 करोड़ रुपए के योजना व्यय में भी 273 करोड़ रुपए की कटौती कर दी गई है.

हालांकि अभी यह विवादास्पद है कि यह संकट पैदा कैसे हुआ. मोइली इस संकट के लिए सरकार को दोषी ठहराते हैं. उनका मानना है कि संसाधनों का दुरुपयोग, सरकारी कंपनियों के बढ़ते घाटे तथा गैर-विकास खर्चों पर रोक और 163.90 करोड़ रुपए की बकाया राशि की वसूली में सरकार की असफलता ही इसके लिए दोषी है. हालांकि हेगड़े इसका दोष पांच सालों के लगातार सूखे पर डालते हैं. गैर-योजना खर्च बढ़कर 36 प्रतिशत हो गया है. समाज कल्याण योजनाएं, किसानों पर करों में कटौती तथा राज्य निगमों के प्रधान और जिला परिषदों के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को दी जाने वाली सुविधाएं आदि सरकारी खजाने को खाली करने के बड़े कारण बने हुए हैं. 'डेक्कन हेरॉल्ड' के संपादक के.एन. हरि कुमार ने वित्तीय प्रबंध में गड़बड़ी का आरोप लगाया है. राज्य में वित्तीय अनुशासन में ढील अपने साथ भ्रष्टाचार के बीज भी ले आई. अरक कांड ने आज भी सरकार का पीछा नहीं छोड़ा है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

राज्य सरकार को दोषी ठहराया था.

प्रशासन में राजनीति का कितना दखल है, यह एक उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले एक वर्ष में राजनीतिकों ने 11,500 अधिकारियों के तबादले के लिए सिफारिशें भेजी. इंकाई हलकों में तो यह मजाक ही चल पड़ा है कि "यह मूल्यों पर आधारित राजनीति है. यहां हर चीज एक खास मूल्य पर उपलब्ध है."

जनता पार्टी के शासन में डोनेशन के आधार पर दाखिला देने वाले निजी मेडिकल, इंजीनियरिंग तथा बीएड कॉलेज तेजी से पनपे हैं. बंगलूर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. डी.एम. नानजुंदप्पा कहते हैं, "कर्नाटक में शिक्षा आज काफी विकट स्थिति में है." 1986 में ही 6 नए निजी इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए और सरकार ने विश्वविद्यालय अधिकारियों से परामर्श किए बिना सीटों की संख्या बढ़ा दी. कुल 1672 सीटें बढाई गईं. 'इंडिया टुडे' ने जांच करने पर पाया कि 1672 सीटों में से 'बेची गई' 816 सीटों के लिए 4.9 करोड़ रुपए एकत्रित हुए. शिक्षामंत्री अल्वा इसके पक्ष में दलील देते हुए कहते हैं, "केपिटेशन फीस इसलिए बढ़ाई गई कि कॉलेजों में अब बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं." लेकिन कुलपति नानजुंदप्पा इसका प्रतिवाद करते हुए कहते हैं, "निजी कॉलेजों के पास न तो समुचित उपकरण हैं, न अध्यापक, न परीक्षक और न ही कोई दूसरी सुविधाएं."

औद्योगिक क्षेत्र में भी हालत कोई बेहतर नहीं है. पिछले कई वर्षों से कर्नाटक में कोई बड़ा उद्योग नहीं लगा. 1982 में कर्नाटक देश का पांचवां औद्योगिक राज्य था. अब यह बारहवें नंबर पर आ गया है. यह ठीक है कि छोटे उद्योगों की संख्या बढ़कर 81,571 हो गई थी लेकिन उद्योगमंत्री बी.ए. जीविजिया भी स्वीकार करते हैं कि इनमें से 30 प्रतिशत औद्योगिक इकाइयां बीमार हैं.

विकास योजनाओं में कटौती करने से बचे

रामकृष्ण हेगड़े

'जिम्मेदारी निभाई'

*वरिष्ठ संपादक **प्रभु चावला** और प्रमुख संवाददाता अनीता प्रताप से अपनी घंटे भर की बातचीत में मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े ने अपनी उपलब्धियों और विफलताओं की चर्चा की. उसके अंश:*

• मुख्यमंत्रित्व के पांच साल पूरे करने पर आपको कैसा लगता है?

अच्छा लगता है. मुझे संतोष और पछतावा दोनों हैं. संतोष इसलिए कि अनेक बाधाओं के बावजूद हमने पांच साल पूरे किए. समाज कल्याण और विकास की नई योजनाएं हमने बनाईं और सफल रहे. लेकिन सूखा न पड़ा होता, बिजली की स्थिति ठीक रहती और केंद्र का बेहतर सहयोग मिला होता तो हम बहुत कुछ कर पाते.

• आपको किन मामलों में और बेहतर काम करने की उम्मीद थी?

औद्योगिक क्षेत्र में अपनी सरकार के कामकाज से मैं संतुष्ट नहीं हूं. पर पानी नहीं बरसने से बिजली की आपूर्ति में 80 फीसदी की कमी आई. जहां तक कृषि की बात है, अगर केंद्र ने मेरी योजनाओं में दिलचस्पी ली होती तो ग्रामीण जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आ जाते.

• आपकी सरकार पर वित्तीय कुप्रबंध के आरोप लगाए जाते हैं. आम आदमी भी कहता है कि सरकार दिवालिया हो गई है.

दिवालिया तो नहीं हुई है, हां वित्तीय मुश्किलें जरूर हैं और मैंने कभी भी इसे छिपाने की कोशिश नहीं की.

• आपकी सरकार की आलोचना का एक बड़ा मुद्दा सस्ती लोकप्रियता वाले कार्यक्रमों पर संसाधनों की बरबादी भी है.

मैं नहीं मानता कि ये कार्यक्रम सस्ती लोकप्रियता वाले थे. केंद्र सरकार महंगाई रोकने में असफल रही है. सरकारी कर्मचारी और फैक्टरी मजदूरों का महंगाई भत्ता मूल्य सूचकांक से जुड़ा है, इसलिए महंगाई की उतनी बुरी मार उन पर नहीं

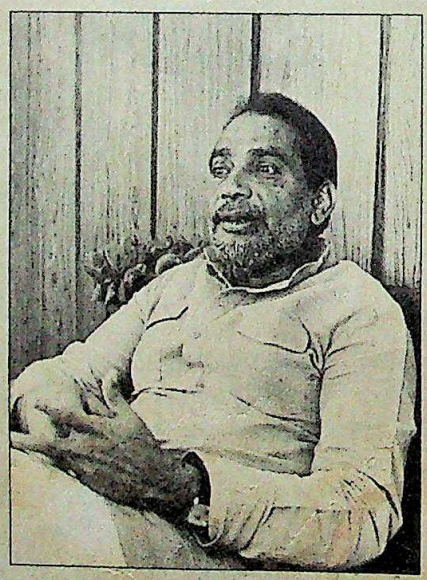

पडती. लेकिन गांववालों का क्या होगा?

• ऐसा लगता है कि जनता सरकार दो बड़ी जातियों के चंगुल में फंस गई है.

यह सही नहीं है, वैसे कोई भी सरकार जाति और संप्रदाय के प्रभाव से बच नहीं सकती. इस मामले में केंद्र सरकार की हालत और भी खराब है.

• क्या सरकार में इन जातियों के दबदबे के कारण आपके राज में हरिजनों पर अत्याचार बढ़े हैं?

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे इंकाशासित राज्यों में हरिजनों पर अत्याचार सैकड़ों गुना अधिक है.

• राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ा है. अरक कांड इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है.

अर्जुन सिंह, भजनलाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की झिड़की का क्या हुआ? अगर राजीव गांधी मूल्यों की थोड़ी भी परवाह करते हैं तो वे इस्तीफा दे दें.

• केंद्र किस तरह से राज्यों से भेदभाव करता आ रहा है?

औद्योगिक लाइसेंस देने, सूखा राहत वगैरह में केंद्र गैर-इंकाशासित राज्यों के साथ भेदभाव करता है.

• पर आम आदमी को इंका और जनता पार्टी सरकार में कोई फर्क नहीं दिखता.

लोगों को अंतर नजर आया है, वरना वे चार बार हम पर भरोसा जाहिर नहीं करते. मैंने अपने बेटे के खिलाफ न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं. आजादी के बाद क्या किसी कांग्रेसी मुख्यमंत्री ने ऐसा किया?

• कहा जाता है कि विपक्षी दलों में एका नहीं हो पाने के कारण राष्ट्रीय नेता बनने की आपकी महत्वाकांक्षा मुरझा गई.

मैंने यह पहले भी कहा है और अब भी कहता हूं कि मेरी कोई निजी महत्वाकांक्षा नहीं है. मेरी पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी सौंपी उसे मैंने पूरी क्षमता से निभाने की कोशिश की है. मैं कभी भी सत्ता के पीछे नहीं भागा. पंचायती राज के गठन के बाद मेरी जिम्मेवारी खत्म हो गई है, मेरे इस बयान को जानबूझ कर उलटे-सीधे रूप में प्रचारित किया गया.

• इतिहास में आपकी सरकार को किस चीज के लिए याद किया जाएगा?

तीन बातें हैं— नई प्रशासनिक संस्कृति की स्थापना जिससे सरकार जनता के अधिक करीब आ गई है. पंचायती राज की स्थापना और ग्रामीण इलाकों के लिए कल्याण कार्यक्रम शुरू करना.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सभी फोटो भवान सिंह

कुछ इस तरह 1985 में सत्ता की कुर्सी पर बैठे थे हेगड़े; और साथियों द्वारा बधाई: लोकप्रियता

धन का उपयोग लोकप्रियता अर्जित करने वाली योजनाओं में किया गया. इनमें ग्रीन कार्ड योजना, गरीबों को सस्ती दरों पर अन्न तथा कपड़ा उपलब्ध कराने, वृद्धावस्था पेंशन, स्कूली बच्चों को मुफ्त यूनिफार्म और पुस्तकें, महिलाओं को मातृत्व भत्ता तथा मुफ्त मंगलसूत्र वितरण और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरंभ की गई ढेरों कल्याणकारी योजनाएं हैं. कल्याणकारी और सुरक्षा उपायों पर 1982 में केवल 6.4 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे. 1987-88 में यह खर्च 200 करोड़ रुपए हो गया.

लेकिन इतनी खर्चीली योजनाओं के बावजूद लोगों में यह धारणा अभी तक कायम है कि जनता

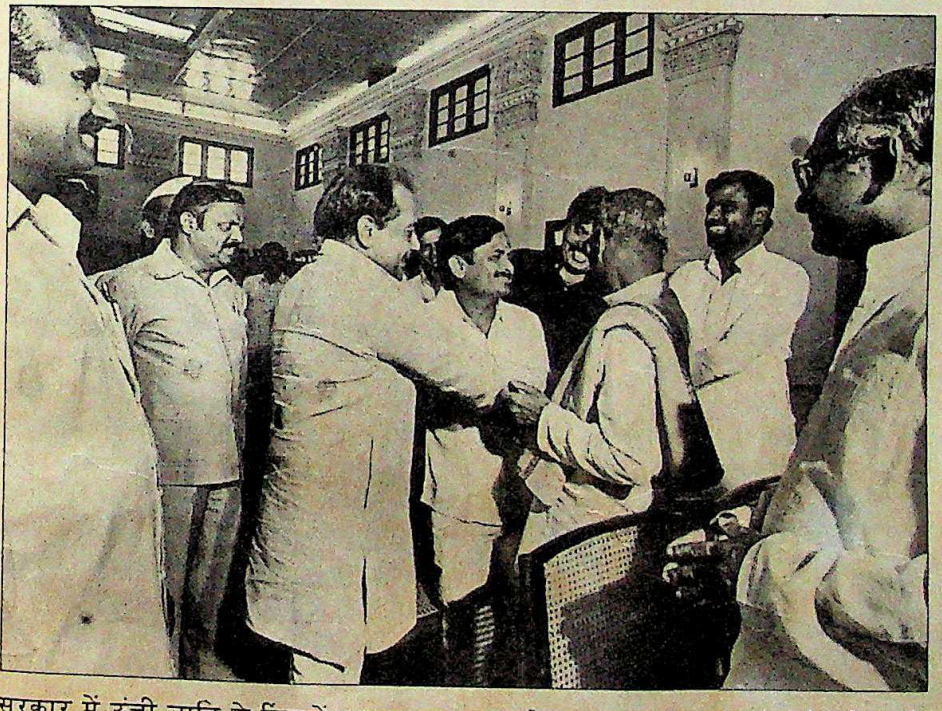

संयोग से जनता पार्टी के संकट के समय हेगड़े सरकार अच्छा काम कर रही थी और 1985 में जब उसे पूर्ण बहुमत मिल गया तब से उसके कामकाज का स्तर गिरता ही चला गया

सरकार में ऊंची जाति के हिंदुओं का दबदबा है. बंगलूर के 'इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोसियो-इकानॉमिक चेंज' के डॉ.एम.बी. नाडकर्णी का कहना है कि "देवराज अर्स द्वारा आरंभ की गई क्रांति को जनता सरकार ने समाप्त कर दिया है." जब अर्स सत्ता में थे तो पिछड़े वर्ग के लोग भी महत्वपूर्ण पदों पर पहुंच गए थे. लेकिन अब फिर राजनीति में वोक्कालिगा तथा लिंगायत आदि ऊंची जातियों के लोगों का प्रभुत्व बढ़ गया है.

लेकिन यह मानने वाले भी कम नहीं हैं कि कम-से-कम कुछ समस्याएं तो केंद्र के असहयोगपूर्ण रवैये की ही उपज हैं. माकपा विधायक के.एस. कृष्णन भी कहते हैं कि केंद्र के पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण जनता सरकार कई योजनाओं पर अमल नहीं कर पाई है.

इंका ने जनता सरकार की समस्याओं से फायदा उठाने में बेहद तत्परता दिखाई है. प्रदेश इंका अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री जनार्दन पुजारी के नेतृत्व ने टूटने के कगार पर खड़ी इस पार्टी में नए प्राण फूंक दिए हैं. लेकिन इससे फायदा जनता नेताओं को भी हुआ है. इंका के नए संगठन से वे भी चौकन्ने हो उठे हैं.

हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में हेगड़े अब भी लोकप्रिय हैं पर विधानसभा के आगामी चुनावों में उनकी पार्टी की जीत निश्चित नहीं है. लोगों को यह भान होना कि हेगड़े अब अपनेआप को कर्नाटक तक सीमित नहीं रखना चाहते, कि उनका मंत्रिमंडल आभाहीन हो चुका है तथा उनका प्रशासन भ्रष्ट और निकम्मा है, 1990 के विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी के विजय के अवसरों को धुंधला कर सकता है. बुजुर्ग नेता निजलिंगप्पा चेतावनी देते हैं कि "यदि आने वाले दो वर्षों में जनता सरकार स्थिति सुधारने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाती तो उसकी हार निश्चित है."

इस चेतावनी को जनता पार्टी गंभीरता से ले, यही उसके हित में होगा.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आंध्र प्रदेश

बेमिसाल अदालती फैसला

और मामलों में ऐसी जल्दबाजी हाईकोर्ट ने कभी नहीं दिखाई

फैसला जितना अस्वाभाविक था, उसे सुनाने में की गई जल्दबाजी उससे कहीं ज्यादा अस्वाभाविक रही. 2 जनवरी को, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के. भास्करन ने टेलीफोन करके दोनों पक्षों के वकीलों को बुलाया और 139 पृष्ठ का अंतरिम फैसला सुना दिया. आश्चर्य यह है कि हाईकोर्ट के पांच न्यायाधीशों की खंडपीठ के सामने मुख्यमंत्री रामराव के खिलाफ दायर की गई इस याचिका की अंतिम सुनवाई 48 घंटे पहले ही पूरी हुई थी. फैसले के अनुसार प्रथम दृष्ट्या सबूत के आधार पर रामराव को पांच मामलों में पद के दुरुपयोग तथा दूसरे दो मामलों में राज्य सरकार को निरंकुश और गैर-कानूनी रवैया अपनाने के लिए दोषी पाया गया.

ये मामले उन 196 आरोपों में से हैं जिनके आधार पर पिछले साल 24 अगस्त को इंका के समुद्रतटीय जिलों के संगठनमंत्री द्रोणमराजू सत्यनारायण ने सार्वजनिक हित में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इसमें अदालत से मांग की गई थी कि वह केंद्र सरकार को इन आरोपों की जांच के लिए आयोग बिठाने का निर्देश दे. अदालत से रामराव के कथित आर्थिक अपराधों के लिए प्रवर्त्तन निदेशालय को उन पर मुकदमा चलाने के निर्देश देने की भी मांग की गई थी. पर अदालत ने इसे नामंजूर कर दिया.

फैसले का समय तथा इसमें की गई अस्वाभाविक जल्दबाजी आश्चर्यजनक है. 30 दिसंबर को अदालत ने कुछ सरकारी फाइलें पेश करने का निर्देश दिया था. लेकिन फाइलें अदालत में आने से पहले ही फैसला सुना दिया गया. 139 पेज का फैसला शनिवार को पांचों न्यायाधीशों से विचार-विमर्श के बाद सुनाया गया. वैसे शनिवार को आम तौर पर अदालत में काम का दिन नहीं होता और तिस पर संक्रांति की छुट्टियों के लिए अदालत बंद भी हो चुकी थी. अदालत ने सत्यनारायण की जांच आयोग बैठाने की मांग इस आधार पर नकार दी कि मांग उठाने का तरीका सही नहीं है. लेकिन इसके बावजूद सात मामलों में उसे प्रथम दृष्ट्या सबूत मिल गए.

इस फैसले की घोषणा से मुख्यमंत्री तथा तेलुगु देशम पार्टी दोनों ही भौचक रह गए. इसकी मुखालफत के लिए पार्टी के विधायक, सांसद और जिला परिषदों तथा जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष वगैरह हैदराबाद में बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए. इस सभा में पारित प्रस्ताव में कहा गया, "अदालत किसी मुख्यमंत्री की रचनात्मक जिम्मेदारी के सिद्धांत को जरूरत से ज्यादा दूर खींच ले गई है. ऐसा करते हुए अदालत ने यह बताना भी जरूरी नहीं समझा कि मुख्यमंत्री ने अपने पद और अधिकारों का दुरुपयोग किस तरह किया है."

मशहूर वकील तथा तेलुगु देशम के सांसद ई. अय्यपु रेड्डी का कहना था, "अदालत ने न तो केंद्र सरकार को निर्देश दिए जाने की मांग मंजूर की है और न ही सात मामलों पर कोई अंतिम फैसला सुनाया है. लेकिन इंका हायतौबा मचाने में लगी हुई है." फैसले पर इंकाई नेताओं की प्रतिक्रिया में भी इस आरोप की सचाई झलकती है. फैसले के कुछ ही घंटे बाद इंका ने मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया. उधर भाकपा की राज्य कमेटी ने भी इंका के सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया.

अपने जवाब में तेलुगु देशम पार्टी के संसदीय दल के नेता पी. उपेंद्र का कहना था,

हाईकोर्ट की पांच सदस्यीय खंडपीठ को पांच मामलों में रामराव द्वारा पद के दुरुपयोग तथा दो मामलों में सरकार द्वारा गैरकानूनी और एकतरफा कार्रवाई करने के प्रथम दृष्ट्या सबूत मिल गए

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रमोद पुष्करणा

तेलुगु देशम के नेता पी. उपेंद्र ने कहा कि सार्वजनिक हित के 3000 मामले लटके पड़े होने के बावजूद हाईकोर्ट ने सिर्फ इसी मामले में गैरजरूरी जल्दबाजी दिखाई

बावजी/जनता स्टुडियो

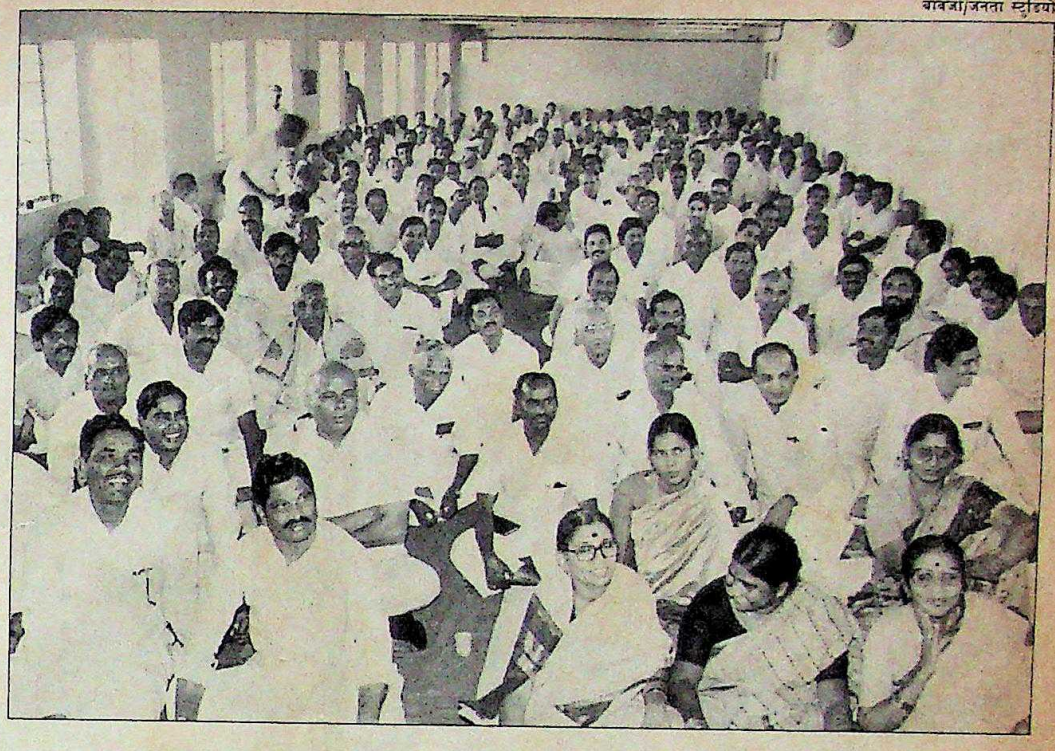

"अदालतों में सार्वजनिक हित के करीब 3,000 मामले पड़े हुए हैं. लेकिन उन सभी मामलों को परे रखकर अदालत ने इस मामले में अनावश्यक जल्दबाजी दिखाई है. अदालत ने इस मामले में असाधारण दिलचस्पी दिखाते हुए केवल वादी द्वारा दिए गए तथ्यों और इन आरोपों को नकारने के लिए दायर किए गए एक मामूली हलफनामे के आधार पर ही अपना फैसला सुना दिया. हमारी अदालतों के लिए यह एक अनहोनी बात है."

अदालत ने प्रथम दृष्ट्या आधार पर रामराव के विरुद्ध पद के दुरुपयोग के इन आरोपों को मुकदमे योग्य पाया है:

► इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन बनाने के लिए सहयोगी-प्रवर्तक के चयन की प्रक्रिया में घपला किया गया तथा रामराव के छोटे दामाद नरेन राजन को लाभ पहुंचाने के लिए केसीपी लिमिटेड को मोहरा बनाया गया.

► रामकृष्ण सिने स्टुडियो की जमीन को 'विशेष औद्योगिक प्रयोग' श्रेणी से बदलकर उसे 'शॉपिंग कांप्लेक्स तथा कल्याण मंडपम बनाने के लिए आम व्यावसायिक प्रयोग' श्रेणी में डाल दिया गया. अनधिकृत निर्माण को मंजूरी देने के लिए नगर निगम के जुर्माने की दर को 20,000 रुपए से घटाकर 1,000 रुपए कर दिया गया. स्टुडियो के लिए उपलब्ध कराई गई 1,200 वर्ग गज सरकारी जमीन की कीमत 40 रुपए प्रति वर्ग गज से घटाकर 14 रुपए प्रति गज कर दी गई. स्टुडियो को यह जमीन इंका सरकार ने उपलब्ध कराई थी.

► रामकृष्ण सिने स्टुडियो के फिल्म उद्योग केंद्र के रूप में काम बंद करने के बाद भी शहरी जमीन सीमा अधिनियम के तहत छूट वापस नहीं ली गई ताकि रामराव के परिवार के सदस्यों को लाभ हो सके.

ये आरोप राज्य में इंका के समुद्रतटीय जिलों के संगठनमंत्री द्रोणमराजू सत्यनारायण द्वारा लगाए गए 196 आरोपों का हिस्सा हैं

स्पंपस इंडिया

तेलुगु देशम कार्यकर्ता इस फैसले को मुख्य न्यायाधीश की उम्र के दावे पर सुप्रीम कोर्ट में लंबित विशेष अनुमति याचिका से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं

फैसले के विरोध में तेलुगु देशम के सांसद और विधानसभा सदस्य

► उनके पुत्रों के 35 मिमी तथा 70 मिमी वाले सिनेमाघरों की 1984 और 1985 के उन दिनों के लिए भी मनोरंजन कर में 1.57 लाख रुपए की छूट दी गई जब वे बंद थे.

► नरेन राजन तथा मुरली कृष्ण को मिनी स्टील प्लांट के लिए जल्दबाजी में कर्ज दिए गए जबकि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने ऐसी इकाइयों पर कर्ज देने पर पाबंदी लगाई हुई थी.

► विजयवाड़ा आयरन ऐंड हार्डवेयर मर्चेंट्स एसोसिएशन को 54 एकड़ जमीन पर दी गई छूट मनमानी और गैरकानूनी थी. इसी प्रकार हैदराबाद विकास प्राधिकरण से 22 एकड़ जमीन खरीदने के लिए कृषि बाजार समिति द्वारा 3.5 करोड़ रुपए देने का निर्णय भी मनमाने और गैरकानूनी ढंग से किया गया.

अदालत के फैसले के बाद रामराव अखबार वालों से मिलने से बचते रहे. लेकिन 4 जनवरी को अपने दल के सांसदों तथा विधायकों की सभा में उन्होंने बड़े नाटकीय ढंग से 'सार्वजनिक हित में' पदत्याग का प्रस्ताव रख दिया. उन्होंने यह नाटकीय बयान मंत्रिमंडल

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

द्वारा हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए विशेष अनुमति याचिका दायर करने के निर्णय के तुरंत बाद दिया.

अपने फैसले में हाईकोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार से आयोग बैठाने को कहना उसके लिए उचित नहीं है. लेकिन अगर मुख्यमंत्री खुद ही इसकी मांग कर देते तो इंकाइयों का हमला कमजोर पड़ जाता. इसके बदले उन्होंने लोगों से सहानुभूति पाने का फैसला लिया. रामराव ने राज्य सचिवालय के कर्मचारियों की एक विशाल सभा में भाषण दिया, उन्होंने उनके महंगाई भत्ते में वृद्धि तथा 1986 में 53 दिनों की हड़ताल में शामिल कर्मचारियों के खिलाफ मामलों की वापसी की घोषणा की. सत्ता के पांच साल पूरा करने पर 9 जनवरी को रामराव ने कई लोकप्रिय कदमों की घोषणा की.

यही नहीं, तेलुगु देशम के कुछ कार्यकर्ताओं

नक्सलवादी

सरकार की जान आफत में

दो दिन तो आंध्र प्रदेश सरकार की जान आफत में रही. पूर्वी गोदावरी जिले के एक जंगल में नक्सलवादियों ने पांच आईएएस अधिकारियों और एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी को बंदूक की नोंक पर बंधक बना लिया. फिरौती के रूप में वे जेल में बंद आठ कट्टर नक्सलवादियों की रिहाई चाहते थे. सरकार को आखिर घुटने टेकने पड़े और अफसरों के बदले आठों नक्सली बंदियों को रिहा कर दिया गया.

घाटे के इस अभूतपूर्व सौदे के सदमे से उबरने में रामराव सरकार को कुछ समय लगा लेकिन सवाल यह है कि आतंकवादियों की इस सफलता से क्या देश के दूसरे आतंकवादियों को भी ऐसे हथकंडे अपनाने की प्रेरणा मिलेगी? पिछले पखवाड़े इन अधिकारियों द्वारा फिर से अपना काम शुरू करने के बाद भी राज्य सरकार इस कांड के खतरनाक परिणामों का लेखा-जोखा करने से कतरा रही थी.

इस नाटक की शुरुआत 27 दिसंबर के दिन दोपहर बाद 3.30 बजे शुरू हुई जब दारला-गड्डा में जैतूनी हरे रंग की वर्दियों में राइफलों से लैस कोंडापल्ली सीतारमैया की अगुआई वाले 'पीपुल्स वार ग्रुप' के दस नक्सलवादियों ने पांच जीपों में आ रहे 25 अधिकारियों के एक काफिले को रोक लिया. ये लोग ओडीसा की सीमा से लगने वाले गुरतेदू में आदिवासी कल्याण योजनाओं का लेखा-जोखा करने के बाद लौट रहे थे. आतंकवादियों ने सब लोगों से हाथ ऊपर उठाए रखने और तलाशी देने को कहा. जीपों की चाबियां लेने के बाद वे अपने साथ आठ वरिष्ठ अफसरों को लेकर जंगल में चले गए. उन्होंने बाकी लोगों को गुरतेदू लौट जाने और तब तक वहां इंतजार करने का निर्देश दिया जब तक उनके 'कामरेड' जेल से रिहा नहीं कर दिए जाते.

बंधक बनाए गए लोगों में सरकार के प्रमुख सचिव एस.आर. शंकरन (53), पूर्वी गोदावरी जिले के कलेक्टर एम.वी.पी.सी. शास्त्री (37), गिरिजन कॉफी के विशेष कार्याधिकारी वी.एम. मनोहर प्रसाद (36), एकीकृत वनवसी विकास एजेंसी के प्रोजेक्ट अफसर टी. विजय कुमार (31), रामपचोडवरम के सब-कलेक्टर आर. सुब्रमण्यम (25) और काकीनाडा के असिस्टेंट कलेक्टर एस. नरसिंह राव (29). प्रसाद के सिवा बाकी सभी आईएएस अधिकारी हैं.

पूर्वी गोदावरी जिले की कलेक्टर टी. राधा (33) और राजामुंदरी जिले की सहायक कलेक्टर पुष्पा थंबी (26) को यह हिदायत देकर छोड़ दिया गया कि वे जाकर जिला पुलिस के मुखिया डी.टी. नायक को उन आठ नक्सलियों को रिहा करने का संदेश दें जिन्हें 15 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था. नक्सलवादियों ने फिरौती की मियाद 29 दिसंबर दिन के 11 बजे तक रखी. दोनों अधिकारी 140 किमी दूर राजामुंदरी तक गईं और नायक को नक्सलवादियों की मांग की सूचना दी.

रात होते-होते राजधानी के सरकारी क्षेत्रों में अच्छी-खासी हलचल मच गई. सरकारी रणनीति के संचालन के लिए आनन-फानन तीन लोगों की एक समिति गठित कर दी गई. उधर केंद्र से गृह मंत्रालय ने भी सक्रियता दिखाई और बूटा सिंह व पी. चिदंबरम ने एनएसजी के 100 कमांडो और केंद्रीय आरक्षित पुलिस के 200 जवानों को विमान से वहां पहुंचाने का आदेश जारी कर दिया.

आकाशवाणी पर यह खबर सुनकर कि विमान से कमांडो भेजे जा रहे हैं, नक्सलियों में तनाव छा गया. एक बंधक अधिकारी ने बताया, "इस समाचार ने उन्हें काफी उत्तेजित कर दिया. उनमें से एक-दो ने तो यहां तक कह दिया कि अगर हमला हुआ तो तुम लोगों को भी हमारे साथ मरना होगा."

कमांडो विशाखापत्तनम पहुंचने लगे पर राज्य के अधिकारी अभी असमंजस में थे कि उन्हें गोदावरी जंगलों में भेजा जाए या नहीं. खुफिया पुलिस के प्रधान एच.जे. डोरा ने अफसरों के सकुशल बंधकों को छुड़ा लाने की कई योजनाओं पर विचार किया लेकिन उन्हें बीच में ही छोड़ दिया गया. डोरा का

बंधक बनाए गए अधिकारी

एस.आर. शंकरन

एम.वी.पी.सी. शास्त्री

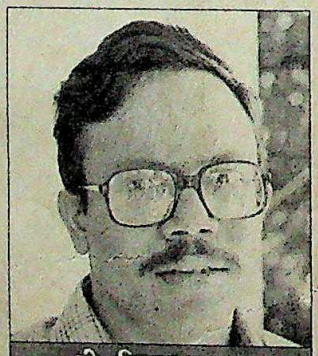
टी. विजय कुमार

आर. सुब्रमण्यम

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ने अदालत की अंतरिम फैसला देने में की गई जल्दबाजी को मुख्य न्यायाधीश भास्करन की उम्र पर चल रहे विवाद से जोड़ने का प्रयास किया. इस विवाद पर पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका दायर है. उनका तर्क है कि अगर भास्करन की उम्र पर विवाद के मामले को सुप्रीम कोर्ट स्वीकार कर लेता तो रामराव के खिलाफ हाईकोर्ट के फैसले का औचित्य स्पष्ट हो जाता.

लेकिन रामराव की परीक्षा की घड़ी खत्म नहीं हुई है. श्रीकालहस्ती और व्यालपाड के विधानसभाई क्षेत्रों के उपचुनाव 20 जनवरी को होंगे. दोनों क्षेत्र उनके दामाद चंद्रबाबू नायडू के गृह जिले चित्तूर में हैं. इनके नतीजों से ही पता चलेगा कि मतदाता मुख्यमंत्री और उनके परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में क्या सोचते हैं.

—अमरनाथ के. मेनन

कहना था, "कमांडो कार्रवाई का मतलब दोनों ओर भारी खून-खराबा होता क्योंकि हमारे पास न तो उस इलाके की सही जानकारी थी और न नक्सलवादियों की शक्ति का सही अंदाज."

कमांडो दस्तों को आम लोगों की नजरों से दूर विशाखापत्तनम के पूर्वी नौसेना मुख्यालय में रखा गया था. तब तक मुख्यमंत्री रामराव ने बंदी नक्सलियों को रिहा करने का फैसला कर लिया था क्योंकि उन्हें डर था कि अगर हालत बिगड़ने दी गई तो केंद्र सरकार उन पर कानून और व्यवस्था को नियंत्रण में न रख पाने का आरोप लगा देगी. यह फैसला होते ही सिर्फ यही तय करना बाकी रह गया कि अदला-बदली का कार्यक्रम किस तरह बिना परेशानी पूरा किया जाए? इस मामले में औद्योगिक सचिव बी.एन. युगांधर ने आंध्र नागरिक अधिकार समिति के अध्यक्ष और पेशे से वकील के.जी. कन्नाबिरन को भी इस नाजुक मामले में सरकार को सहयोग देने के लिए तैयार रहने का आग्रह किया पर संचार और प्रक्रिया में होने वाली देरी के कारण अदला-बदली का कार्यक्रम दो बार टल गया. आखिर 29 दिसंबर रात आठ बजे युगांधर और कन्नाबिरन राजामुंदरी केंद्रीय जेल से आठों कैदियों को लाए.

इस अदला-बदली के बाद कन्नाबिरन का कहना था, "यह छोटा-सा हनीमून अब पूरा हो गया. अब मैं फिर से दूसरे पक्ष की ओर से मानवाधिकारों के लिए संघर्ष करूंगा." इस सारे कांड में हास्यास्पद बात यह रही कि वह सरकार जो कन्नाबिरन को नक्सलवादी कहती आ रही थी, उन्हीं की मदद लेने पर मजबूर थी. इतनी ही हास्यास्पद बात यह रही कि दलितों के लिए संघर्ष करने का दावा करने वाले नक्सलवादियों ने ऐसे अफसरों को बंधक बनाया जो आदिवासियों के कल्याण कार्यक्रमों को लगन से लागू करने के लिए मशहूर हैं. उदाहरण के लिए शंकरन अपने सादे रहन-सहन और आंध्र तथा पड़ोसी राज्यों के दूरदराज के गांवों में जाकर आदिवासियों के दुख-दर्द को समझने के लिए काफी चर्चित हो चुके हैं.

बंधक कांड ने राज्य पुलिस की छवि को काफी धूमिल किया है जो नक्सलवादियों पर नियंत्रण में हाल ही की कुछ सफलताओं के कारण सुधर रही थी. इससे पहले यह छवि तथाकथित 'मुठभेड़ों' के कारण पहले भी खराब हो चुकी है. इस बारे में नायक का कहना था, "इस घटना से हमारी काफी उपलब्धियों पर पानी फिर गया है. समय के इस नुकसान की भरपाई कर पाना बहुत ही कठिन होगा."

मगर इस पूरे कांड में असली नुकसान आदिवासियों को हुआ है क्योंकि अब वरिष्ठ अफसर बिना पुलिस सुरक्षा के आदिवासी इलाकों में जाने से कतराएंगे और इसका असर कल्याण कार्यक्रमों की गति पर पड़े बिना नहीं रह सकता.

—अमरनाथ के. मेनन रामपचोडवरम में

रिहा किए गए नक्सलवादी

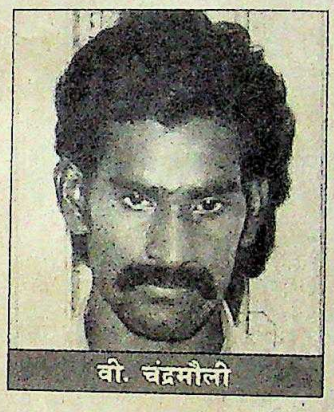
वी. चंद्रमौली

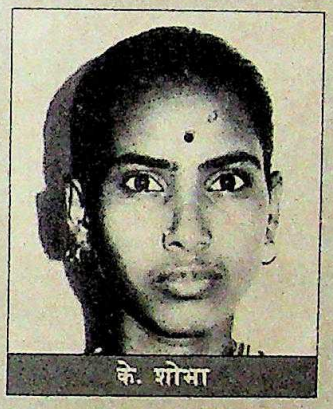
के. शोभा

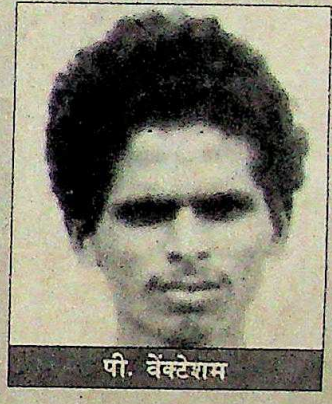
पी. वेंकटेशम

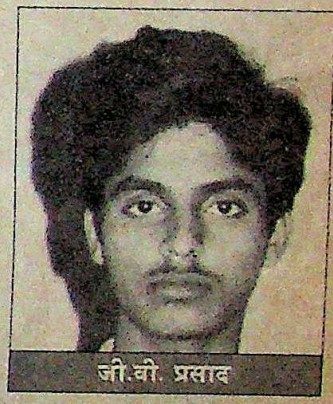
जी.वी. प्रसाद

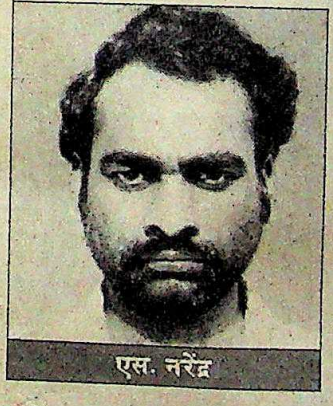
एस. नरेंद्र

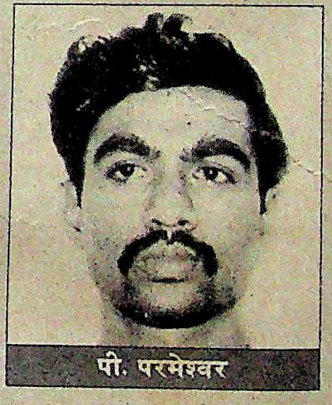
पी. परमेश्वर

एस. राजेश्वरी

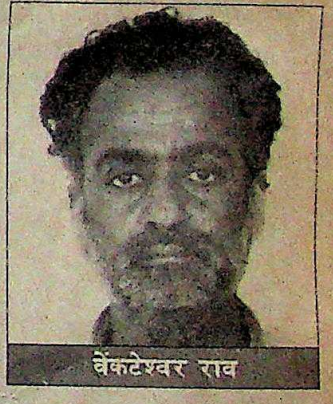
वेंकटेश्वर राव

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

फेयरफैक्स

शांत जल में फिर हलचल

आरोपों-प्रत्यारोपों से विवादास्पद मामले को नया मोड़

"हमारे पुराण ऐसे राक्षसों की कथाओं से भरे पड़े हैं जो छल करने, अफवाहें फैलाने, जादू-टोना करने तथा मायाजाल बिछाने में माहिर थे."

—फेयरफैक्स विवाद पर वाशिंगटन में भारतीय दूतावास के वकील डी.एस. शास्त्री

राक्षस हो या नहीं पर पिछले पखवाड़े फेयरफैक्स के धुंधलाए दृश्यपटल पर ऐसा ही एक शख्स अचानक कहीं से उभर आया और देखते ही देखते उस पर छा गया. ये शख्स हैं अली सिद्दीकी, जो लंबे अरसे से नेहरू-गांधी खानदान और उनके खासमखास मुहम्मद यूनुस की चापलूसी करते रहे और आजकल यूनुस के स्वनामधन्य बेटे आदिल शहरयार के कंप्यूटरों के धंधे में हाथ बंटा रहे हैं. फेयरफैक्स मामले में उन्होंने ऐसे कई सनसनीखेज दावे किए कि कल्पनाथ राय और कमलकांत तिवारी जैसे तीसमारखां भी पीछे छूट गए.

उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी गुप्तचर संस्था फेयरफैक्स समूह के अध्यक्ष माइकल हर्शमैन ने पूर्व वित्तमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह से दो बार मिलने की बात उनके सामने कबूल की है. उनका यह भी दावा है कि हर्शमैन ने उनसे कहा कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उनसे 34 बड़े आप्रवासी भारतीयों के वित्तीय घोटालों की जांच करने को कहा था. हालांकि सिद्दीकी ने यह नहीं बताया कि अमेरिका में 'निजी तौर पर' यह छानबीन करने के लिए उन्हें पैसे किसने दिए. मगर उनका यह भी कहना है कि 'व्यक्तिगत दिलचस्पी' के कारण ही उन्होंने यह जांच की.

लेकिन उनके अतीत के कारण उनके इरादे संदेह के दायरे में आ जाते हैं. उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत सड़कछाप किताबें छापने और नेहरू-गांधी परिवार पर प्रदर्शनियों के आयोजन से की थी. हैदराबाद की पुलिस फाइलों में उनके बारे में कई दिलचस्प बातें दर्ज हैं. मसलन 1979-80 में सिद्दीकी अल-जम-जम के नाम से एक कंपनी चलाया करते थे. इस कंपनी ने अरब देशों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर कई इच्छुक लोगों से पैसे ऐंठे.

उन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह को बचाव की मुद्रा में आने के लिए मजबूर कर दिया.

दावे	जवाबी दावे

अली सिद्दीकी (57), स्वयंभू फोटो-पत्रकार, कंप्यूटर विशेषज्ञ और नेहरू-गांधी परिवार के चिरकालीन समर्थक.

"हर्शमैन ने बताया कि वे दो बार वी.पी. सिंह से मिले जिन्होंने बोफोर्स घोटाले की छानबीन और 34 आप्रवासी भारतीयों की वित्तीय स्थिति की जांच करने को कहा"

माइकल हर्शमैन (41), अमेरिकी गुप्तचर एवं प्रबंध सलाहकार कंपनी फेयरफैक्स समूह के अध्यक्ष और अमेरिकी कांग्रेस के पूर्व गुप्तचर.

"हम वी.पी. सिंह से कभी नहीं मिले. हमारा संपर्क तो भारतीय वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से ही रहा"

लतीफ खां (43), शिकागो के भारतीय व्यापारी जिन्होंने आप्रवासी भारतीयों के खातों की अवैध छानबीन के आरोप में फेयरफैक्स पर मुकदमा किया है.

"हमने हर्शमैन से यही कहा कि यदि वे फीस का भुगतान न किए जाने के कारण ठक्कर-नटराज़न आयोग की मदद नहीं कर रहे तो हम उनकी फीस चुकता करेंगे"

"हमें घूस देने की पेशकश लतीफ़ खां के वकीलों ने टेलीफोन पर की थी"

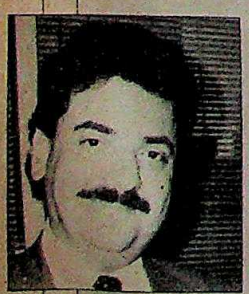

हेरॉल्ड रोज़ेन (47), शिकागो की कानूनी सलाहकार कंपनी वोलिन ऐंड रोज़ेन के भागीदार और खां के वकील, जिन पर हर्शमैन ने घूस की पेशकश का आरोप लगाया है.

"हम तो उनसे (हर्शमैन से) एक ही बार मिले थे. बाद में उन पर मुकदमा दायर किया. यदि भारतीय जनता उनके रिकार्ड की छानबीन करे तो पता चलेगा कि उनका आरोप बहाना है"

"हम कुछ नहीं छिपाते. अदालत को हमने जवाब दे दिया है. अब फैसला उसी के हाथ में है"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उन्हें हर्शमैन के साथ अपनी कथित मुलाकात के आरोप का जोरदार खंडन करना पड़ा. इसी दरम्यान हर्शमैन ने इस विवाद में अब एक और अध्याय जोड़ दिया है. उनका आरोप है कि शिकागो में रहने वाले एक भारतीय नागरिक लतीफ खां और उनका प्रतिनिधित्व करने वाली एक वकालत फर्म वोलिन ऐंड रोजेन ने उन्हें राजीव गांधी के बेकसूर होने का फतवा देने के लिए 5 लाख डॉलर (65 लाख रुपए) घूस देने की पेशकश की थी. लतीफ खां पेंटागन समूह की निर्माण तथा इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय की कंपनियों के मालिक हैं.

खां का कहना है कि वे सिद्दीकी को हैदराबाद के स्कूल के दिनों से जानते हैं. खां ने पिछले सितंबर में भारत सरकार की ओर से 'नाजायज गतिविधियां' करने के लिए फेयरफैक्स पर मुकदमा ठोक दिया. उनका आरोप है कि फेयरफैक्स अमेरिकी आंतरिक राजस्व सेवा के जरिये आप्रवासी भारतीयों के वित्तीय रिकार्ड हासिल करने की कोशिश कर रहा था.

लगता है कि 'स्कूल के दिनों के' इन दोनों दोस्तों की मुलाकात 24 अगस्त को हुई थी. तब यानी फेयरफैक्स पर मुकदमा दायर करने से एक हफ्ता पहले खां और उनके वकील वाशिंगटन के उपनगर अनांडेल की वर्जीनिया बस्ती में स्थित फेयरफैक्स के दफ्तर में गए थे. खां के वकीलों का कहना है कि वे हर्शमैन से सिर्फ इतना ही कहने गए थे कि वे ठक्कर-नटराजन आयोग से सहयोग करें. हो सकता है कि उस वक्त सिद्दीकी भी वहां मौजूद रहे हों पर उनसे उनका कुछ भी लेनादेना नहीं था. अधिवक्ता हेरॉल्ड रोजेन ने कहा, "जब हम वहां से निकल रहे थे तभी एक दूसरा भारतीय अंदर आया जिसे अंग्रेजी बोलनी नहीं आती थी." पर सिद्दीकी का 'इंडिया टुडे' से कहना था "हमको इंग्लिश-विंग्लिश सब आती हैं."

24 अगस्त की शाम को फेयरफैक्स को घूस देने की कोशिश की गई या नहीं, इसे साबित करना आसान नहीं है. लेकिन खां और उनके वकील का कहना है कि उन लोगों ने हर्शमैन से यह जरूर कहा कि अगर वे ठक्कर-नटराजन आयोग को वित्तीय मामलों की अपनी जांच के नतीजे लिख भेजें तो उनके लिए 'फीस की व्यवस्था की जा सकती है.' खां ने 'इंडिया टुडे' को शिकागो से टेलीफोन पर बताया, "हर्शमैन ने हमसे कहा कि भारत सरकार ने उसकी फीस अदा नहीं की है इसीलिए वह आयोग की सहायता नहीं कर रहा. इस पर हमने कहा था कि हम इस बाबत कुछ कर सकते हैं."

प्रमोद पुष्करणा

इंदिरा गांधी और यूनुस के साथ सिद्दीकी (बीच में) : दागदार दामन

विपक्षी दलों का आरोप है कि खां तो यूनुस का मोहरा हैं. जबकि खां इस सबके पीछे किसी तरह का व्यक्तिगत या राजनैतिक इरादा होने की बात नकारते हैं. उनका अपने बारे में दृढ़ता से कहना है, "मैं देशभक्त भारतीय हूं. मैं हर्शमैन जैसे वाचाल ठग द्वारा वर्जीनिया के 420 नंबर के मकान में बैठकर भारत का अपमान करना या अपने देश के जांच-आयोगों को गलियाना या उसे फर्जी अदालत होने का फतवा देना बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं." लेकिन वे मानते हैं कि फेयरफैक्स जिन आप्रवासी भारतीयों की जांच कर रहा था, उस लिस्ट में हो सकता है उनका भी नाम हो. प्रवर्तन निदेशालय के पूर्व निदेशक भूरेलाल ने भी आयोग को दिए जवाबनामे में लिखा था कि वे भी हवाला धंधे के गड़बड़झाले के सिलसिले में एक खां के मामलों की जांच कर रहे थे.

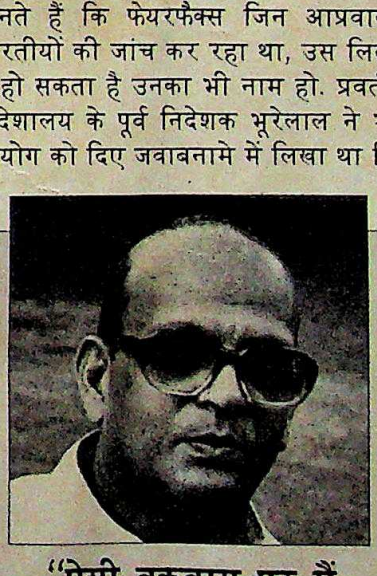

"ऐसी बकवास पर मैं ध्यान नहीं देता. सिद्दीकी जैसे लोगों की औकात ही क्या है"

विश्वनाथ प्रताप सिंह
पूर्व वित्तमंत्री

मजेदार बात यह है कि सिद्दीकी के स्तर को भुलाते हुए आरोपों से घिरा प्रायः हर व्यक्ति अपने बचाव में लग गया है. हालांकि पूर्व वित्तमंत्री ने इन नए आरोपों को एकबारगी नकार दिया है, फिर भी उनका गुस्सा तो जाहिर हो ही जाता है. उन्होंने कहा, "मैं ऐसी बकवास पर ध्यान नहीं देता. सिद्दीकी जैसे लोग कोई औकात नहीं रखते." उनका मानना है कि हर्शमैन से उनकी कभी बातचीत नहीं हुई.

यदि आयोग के नतीजों को अदालत में चुनौती दी गई तो वहां खुफिया और दूसरी जांच करने वाली एजेंसियों के कामकाज के बारे में सवाल उठाए जा सकते हैं. मसलन— राजस्व गुप्तचर निदेशालय हांगकांग, सिंगापुर, काठमांडो, दुबई और लंदन के प्रतिनिधियों से तस्करों के बारे में नियमित सूचनाएं हासिल करता रहा है.

सरकार कानूनदां लोगों की राय का इंतजार करती रही है, साथ ही उसे वाशिंगटन में चल रही कानूनी कार्यवाही पर भी सतर्कता से निगाह रखनी पड़ रही है. वहां हर्शमैन के खिलाफ लतीफ खां के आरोप से अलग राजीव की ओर से हर्शमैन को रिश्वत की पेशकश का मामला भी सुनवाई के लिए अदालत में आएगा. और अदालती फैसलों का फेयरफैक्स मामले पर दीर्घकालीन असर पड़ेगा, बशर्ते कि अमेरिकी न्यायाधीश ठक्कर-नटराजन आयोग से कुछ ज्यादा ढूंढ़ पाने में कामयाब हो जाएं.

—शेखर गुप्ता और पंकज पचौरी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उत्तर प्रदेश

'दिल' जीतने की लड़ाई

गोरखपुर और सुलतानपुर में वी.पी. सिंह को भारी जनसमर्थन

भारत का राजनैतिक 'दिल' जीतने यानी उत्तर प्रदेश पर कब्जे की लड़ाई बदस्तूर जारी है. शुरुआती लक्षण विपक्ष की ही जीत के संकेत देते हैं. पिछले पखवाड़े जनमोर्चे के नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इस लड़ाई का मोर्चा राज्य में दूर-दूर तक खोल दिया. और उन्हें मिला जनसमर्थन अभूतपूर्व था. यहां तक कि राजीव गांधी के गढ़ अमेठी में भी उन्होंने भारी समर्थन बटोरा.

जिन कांग्रेसियों ने वी.पी. सिंह को 1987 का डूबता सितारा करार दिया था, उन्हें फिर से गौर करना होगा. पूर्व रक्षामंत्री ने इस पखवाड़े उत्तर प्रदेश की अपनी दो यात्राओं में उनके इस दावे को पूरी तरह गलत सिद्ध कर दिया है. इंका सरकार की अड़ंगेबाजी के बावजूद जहां-जहां से वे गुजरे, भारी भीड़ उनके स्वागत में उमड़ आई. 5 जनवरी को जब वे गोरखपुर में निर्धारित समय से पांच घंटे देर से पहुंचे तो भी 75,000 से अधिक लोगों का हुजूम उन्हें सुनने के लिए बेताबी से उनका इंतजार कर रहा था. इससे राज्य के मुख्यमंत्री वीरबहादुर सिंह और उनके समर्थक चकराए ही नहीं बल्कि अमेठी संसदीय क्षेत्र के इन्हौना और जगदीशपुर हलकों से होते हुए सुलतानपुर तक वी.पी. सिंह को मिले भारी सत्कार ने उनकी रही-सही सिट्टी-पिट्टी भी गुम कर दी. सुलतानपुर शहर में तो भीड़ ने करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन किया. जुलूस के आगे-आगे 200 से भी अधिक गाड़ियों का काफिला था. सभास्थल का दो किलोमीटर लंबा रास्ता तय करने में इस काफिले को एक घंटे से अधिक समय लगा.

'प्रधानमंत्री के जिले' में हुई इस ऐतिहासिक सभा में वी.पी. सिंह ने विजेता वाले अंदाज में कहा कि पदारूढ़ नेताओं के खिलाफ जनता के फैसले पर किसी को शक हो तो वह खुद सभा में आकर अपना संदेह निवारण कर ले

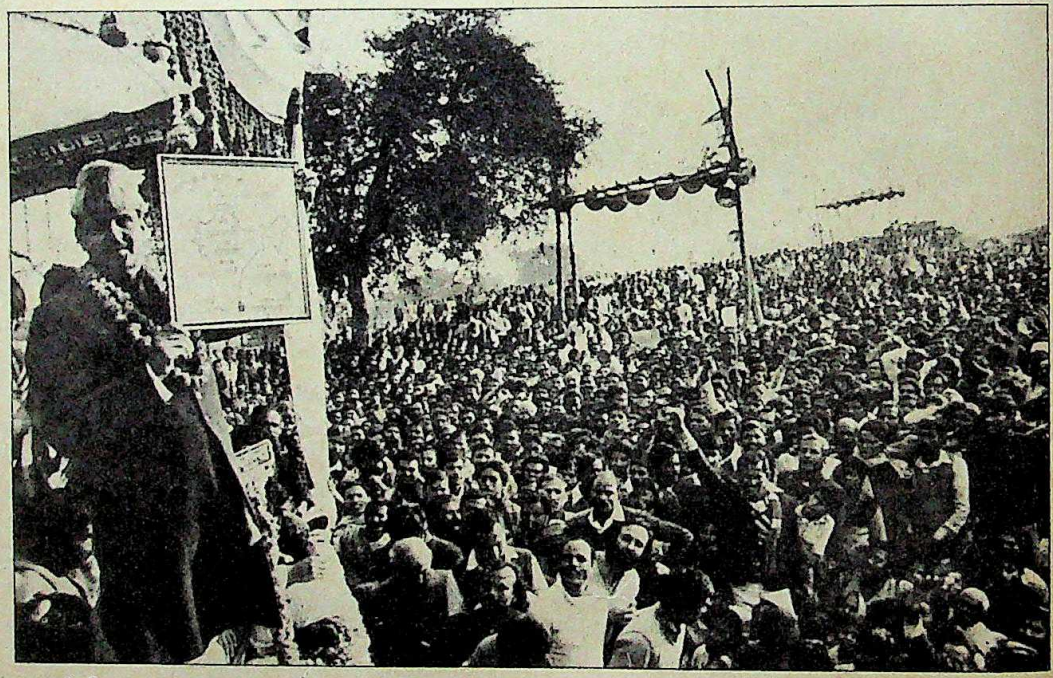

सुलतानपुर में वी.पी. सिंह की सभा

'प्रधानमंत्री के जिले' में हुई यह सभा निश्चय ही ऐतिहासिक थी. वी.पी. सिंह ने विजेता के अंदाज में इस भारी रैली को संबोधित किया. उन्होंने दहाड़ते हुए कहा कि यदि किसी को मौजूदा सत्ताधारी नेताओं के खिलाफ जनता के फैसले पर अभी भी संदेह है तो आज की सभा में वह खुद आकर अपनी शंका का निवारण कर ले.

जनमत को अपने पक्ष में करने की जनमोर्चे की रणनीति बिलकुल साफ और सीधी रही है. उसने आसमान छूती महंगाई, बढ़ते भ्रष्टाचार और आम आदमी की परेशानियों के लिए हमेशा सत्ताधीशों को दोषी ठहराया है, कांग्रेस के बड़े नेताओं की ईमानदारी पर लोगों के दिलों में शंकाएं पैदा की हैं. वी.पी. सिंह के समर्थन में इस्तीफा देने वाले राज्य के पूर्व मंत्री जफर अली नकवी कहते हैं, "सरकार की कमजोरियां और नाकामियां ही हमें मजबूत बनाती हैं." यह रणनीति कारगर भी हुई लगती है. सुलतानपुर के एक गांव में प्राइमरी स्कूल के अध्यापक सियाराम त्रिपाठी टिप्पणी करते हैं, "अधिकांश गांव वाले नहीं जानते कि बोफोर्स क्या बला है पर उन्हें इतना यकीन है कि जनमोर्चा कांग्रेस को गंभीर चुनौती देने लायक हो गया है."

पर जनमोर्चा यह लड़ाई अकेले नहीं लड़ रहा. उसने दूसरे विपक्षी गुटों को भी इसमें साथ लिया है. गोरखपुर की जनसभा में उनके साथ मंच पर जनता पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर और लोकदल (अ) अध्यक्ष अजीत सिंह के अलावा राष्ट्रीय संजय मंच के उपाध्यक्ष अकबर अहमद डंपी भी मौजूद थे. पर नेता निस्संदेह वी.पी. सिंह ही थे. दूसरे सभी नेताओं ने मानो उन्हें ही नायक मान लिया था. भीड़ भी उन्हीं को देखने आई थी. सुलतानपुर की जनसभा में अरुण नेहरू और मुफ्ती मुहम्मद सईद सहित जनमोर्चे के अधिकांश नेताओं तथा विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों तक ने वी.पी. सिंह को महात्मा गांधी के नक्शेकदम पर चल रहे क्रांतिकारी का खिताब दिया. मुफ्ती तो एक कदम और बढ़ गए. उन्होंने वी.पी. सिंह को ऐसे मसीहा तक की उपाधि दे डाली जो देश को बचाने आया है. मंच पर हालांकि विद्याचरण शुक्ल भी मौजूद थे पर उन्होंने भाषण नहीं दिया.

इंका के लिए तो और भी शोचनीय स्थिति

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

थी. वी.पी. सिंह की सभाओं में विघ्न डालने के लिए उसके प्रयास खुद उसके लिए नुक-सानदेह साबित होते रहे हैं. जबसे पूर्व रक्षामंत्री राज्य भर के राजनैतिक अभियान पर निकले हैं, बीरबहादुर उनकी राह में रोड़े अटकाने की कोशिश करते आए हैं. पिछले साल मई और जून में लखनऊ और गोरखपुर की उनकी सभाओं पर प्रतिबंध लगाया गया पर इससे जनमोर्चा नेता को ही मुफ्त में प्रचार मिल गया. उसके बाद इंकाइयों ने वी.पी. सिंह से सीधी टक्कर लेने का दांव चला. उन्नाव और लखीमपुर खीरी में उनके काफिलों पर हमले हुए. उन्नाव की जनसभा में सांप छोड़े गए. 15 दिसंबर को मोदीनगर के सभास्थल को पानी से तर कर दिया गया. इन सब का परिणाम कुछ नहीं निकला, सिवा इसके कि वी.पी. सिंह को अपने श्रोताओं को सुनाने के लिए मजेदार मसाला हाथ लगा.

ताजा दांवपेच भी उतने ही घटिया थे. 4 जनवरी को वी.पी. सिंह को दिल्ली से इंडियन एअरलाइंस के जिस विमान से लखनऊ पहुंचना था उसकी उड़ान आखिरी मौके पर रद्द कर दी गई. एअरलाइंस के मुताबिक यह खराब मौसम के कारण किया गया था. पर वी.पी. सिंह ने इसे खराब राजनीति बताया. फिर उन्होंने दिल्ली से लखनऊ मेल पकड़ी लेकिन लखनऊ से 18 किलोमीटर पहले काकोरी पहुंचकर गाड़ी में खराबी आ गई. मगर जब वी.पी. सिंह गाड़ी से उतरकर कार से रवाना हो गए तो गाड़ी भी चल पड़ी. इसकी वजह से वे गोरखपुर एक बजे के बजाय शाम छह बजे पहुंचे.

अब सत्तारूढ़ पार्टी के दांवपेचों से वाकिफ हो चुके जनमोर्चा नेताओं ने सुलतानपुर की रैली के लिए वी.पी. सिंह की यात्रा की वैकल्पिक व्यवस्था की. सुलतानपुर रैली के मुख्य संयोजक संजय सिंह कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि इंका को मात देने के लिहाज से इसका भारी महत्व था बीरबहादुर को नीचा दिखाने की गरज से संजय सिंह ने वी.पी. सिंह की यात्रा का भारी बंदोबस्त किया था. वी.पी. सिंह ने हालांकि इंडियन एअरलाइंस का टिकट ले रखा था, पर विमान से जाने के बजाय इस बार फिर उन्होंने लखनऊ मेल पकड़ी. वे बताते हैं, "चढ़ने से पहले ही किसी ने मुझे आगाह किया कि विमान खराब मौसम के बहाने लखनऊ पड़ाव न डालकर सीधे कलकत्ता जाकर उतर सकता है." संजय सिंह और उनके समर्थकों ने शाहजहांपुर से आगे कार का इंतजाम कर रखा था लेकिन गाड़ी ठीकठाक पहुंचने के कारण उसे इस्तेमाल करने की नौबत ही न पड़ी.

जनमोर्चा नेताओं का काफिला

इस बीच लखनऊ में मुख्यमंत्री ने विधान-सभा के शीतकालीन अधिवेशन की कार्य-वाही एक दिन और बढ़ा दी. बताया जाता है कि यह जनमोर्चा समर्थक विधायकों को वी.पी. सिंह की गोरखपुर जनसभा में न पहुंचने देने की एक चाल थी. इस पर इंका विधायक दल ने व्हिप जारी कर अपने सदस्यों को 5 दिसंबर के दिन विधानसभा में हाजिर रहने की ताकीद की. व्हिप की कानूनी पेचीदगियों में जकड़े करीब 25 जनमोर्चा विधायक, जो तकनीकी तौर पर अभी भी इंका में हैं, लखनऊ से नहीं जा सके. विधानसभा से उनकी गैरहाजिरी का मतलब विधायकी से हाथ धोना होता. अधिवेशन 4 जनवरी को खत्म होना था पर विपक्ष ने सत्र बढ़ाए जाने की रस्मी बात कही ही थी कि मुख्यमंत्री ने तुरंत लपक लिया.

राजनैतिक माहौल गरमाने से राज्य विधानसभा के अटके पड़े उपचुनावों का महत्व और बढ़ गया है. यदि इंका आला-कमान मध्यावधि चुनाव की संभावनाएं तलाश कर रहा था और बीरबहादुर उत्तर प्रदेश में ही उपचुनाव कराने की सोच रहे थे तो वी.पी. सिंह की दो यात्राओं ने निश्चय ही उन्हें फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है. जनमोर्चा नेता ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनका जनजागरण अभियान वक्त की आंधी में उड़ने वाला नहीं है जैसा कि बहुत से इंका नेता मानते आए हैं. ऐसे में इंका को विपक्ष के बढ़ते प्रभाव को रोकने की रणनीति पर पुनर्विचार करना होगा.

तमाम अंडंगेबाजी के बावजूद जनमोर्चा नेता जहां-जहां से गुजरे, उनके स्वागत को लोग उमड़ पड़े. प्रदेश इंका के नेताओं की सिट्टी-पिट्टी गुम हो गई है. इंकाई पूछ रहे हैं—अब क्या होगा?

सत्तारूढ़ पार्टी में जनमोर्चे की मुहिम को थामने के लिए कुछ उपाय करने का एहसास जोर पकड़ता जा रहा है. इसका संकेत इंका विधायकों की एक बैठक में एक विधायक के इस प्रश्न से मिलता है— 'अब क्या होगा?' बैठक में चर्चा का मुद्दा था वी.पी. सिंह की गोरखपुर की जनसभा में उमड़ी भारी भीड़ का सबब. इंका विधायक के उक्त सवाल का जवाब चाहे जो हो, मुस्कराहट वी.पी. सिंह के चेहरे पर ही तिरती रही. 'प्रधानमंत्री के जिले' में जनसभा के बाद वे उस रात वहीं रुक गए और हास्य कवि सम्मेलन में मुस्कराते रहे.

—विलीप अवस्थी, सुलतानपुर में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

श्याम टेकवानी

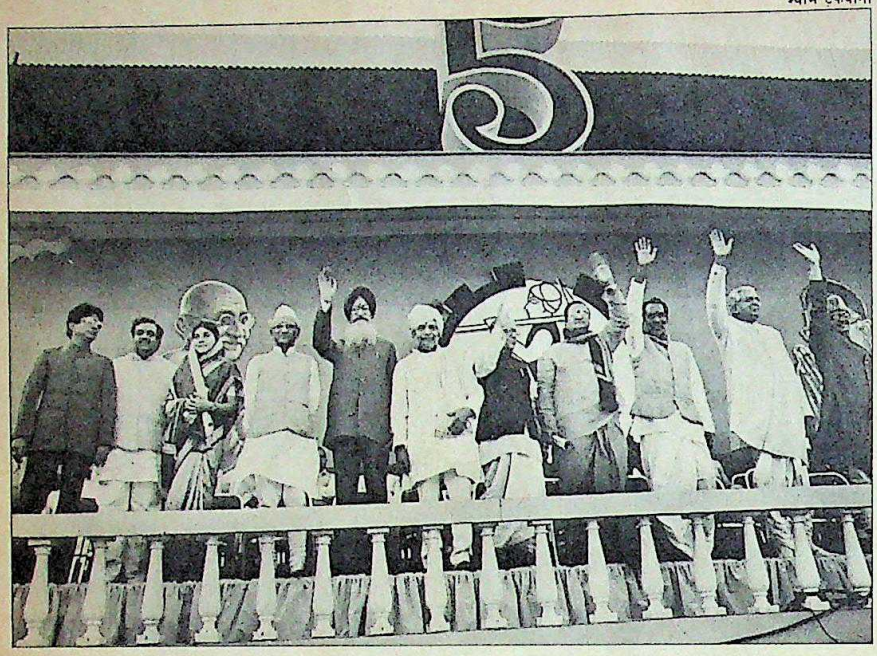

बंगलूर में एका के पक्ष में उठे हाथ

विपक्ष

विकल्प बनाने के मंसूबे

विभाजित विपक्ष के नेता पहली बार एक मुंह से बोले

हाल तक यह सोचा भी नहीं जा सकता था कि विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर, देवीलाल और अजीत सिंह, अरुण नेहरू और मेनका गांधी जैसे विपक्षी नेता भी एक मंच पर जुट सकते हैं. जनता पार्टी के सत्ता में आने के पांच वर्ष पूरे होने पर बंगलूर में हुए 'जनोत्सव' तथा तेलुगु देशम की सरकार के पांच साल पूरे होने पर आयोजित 'विजयोत्सव' पर सारे लोग जुटे.

विभिन्न पार्टियों के नेताओं को अब आपसी बहुत सारी समानताएं नजर आ रही हैं. 12 विपक्षी दलों के, वामपंथी से लेकर दक्षिण पंथी तक, असम से लेकर कन्याकुमारी तक से आए 15 नेताओं ने एक मुंह से विपक्षी एकता की बात कही. उद्देश्य था गिरती साख वाली राजीव सरकार का विकल्प प्रस्तुत करना. बातचीत 'मुद्दों के आधार' पर विपक्षी एकता पर केंद्रित थी. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन.टी. रामराव ने कहा, "भ्रष्ट, तानाशाह और अलोकतांत्रिक इंका सरकार को हटाने के लिए विपक्षी दलों में साझा मुद्दों के आधार पर एकता होनी चाहिए."

इन दलों में एका की कोशिश दो स्तरों पर चल रही है. सरकारों के स्तर पर हो रही कोशिश में विपक्षी मुख्यमंत्री केंद्र के भेदभावपूर्ण कोष वितरण के खिलाफ मिल-कर आवाज उठा रहे हैं. साथ ही राजनैतिक स्तर पर भी मेल-मिलाप की कोशिश चल रही है जिसका एक नतीजा पिछले महीने जनमोर्चा, जनता पार्टी, कांग्रेस (स) और लोकदल (अ) के मोर्चे के रूप में सामने आया. लोकदल (अ) के अध्यक्ष अजीत सिंह कहते हैं, "प्रमुख विपक्षी दलों के विलय का यह पहला कदम साबित हो सकता है."

गैर-इंकाई वोटों का बंटवारा रोकने के लिए विपक्षी दलों में एकता बने, यह बात सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरि-याणा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए ही महत्वपूर्ण है. दक्षिण में अभी क्षेत्रीय दलों—आंध्र में तेलुगु देशम, कर्नाटक में जनता और तमिलनाडु में द्रमुक के रूप में मजबूत विकल्प है ही.

किसी दूसरे बड़े विपक्षी नेता की अनु-पस्थिति में विश्वनाथ प्रताप सिंह ही अभी उत्तरी इलाके में भीड़ और वोट खींचने वाले नेता के रूप में उभर रहे हैं. पर यही बात नवगठित मोर्चे के बारे में नहीं कही जा सकती. हिंदीभाषी क्षेत्र में भाजपा और लोकदल (ब) के शामिल हुए बिना यह मोर्चा विकल्प नहीं बन सकता. इतना ही नहीं, इस मोर्चे को मजदूर वर्ग और अल्पसंख्यक तबकों के वोट दिलाने के लिए कम्युनिस्टों का समर्थन भी जरूरी है. इस दिशा में अब ठोस प्रयास किए जा रहे हैं. वी.पी. सिंह कहते हैं, "हां, लोकदल (ब) को भी मोर्चे में जरूर रहना चाहिए."

वी.पी. सिंह को एहसास हो चुका है कि विपक्षी एकता उन्हीं के इर्द-गिर्द होगी. सो वे इस मोर्चे को अभी ढीलाढाला ही रख रहे हैं. एक ओर उन्होंने देवीलाल से दोस्ती गांठी है और दूसरी ओर वे भाजपा और माकपा से भी मतभेद पाटने की कोशिश कर रहे हैं. वे देवीलाल के साथ अगले पखवाड़े हरियाणा की एक सभा में बोलने जा रहे हैं और देवीलाल भी उनके साथ उत्तर प्रदेश में बोलेंगे. जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने कहा, "हम दूसरे दलों से (विलय या गठबंधन) रणनीति तय कर लेंगे, साथ ही भाजपा और माकपा से सीटों का तालमेल कर लेंगे. इससे ज्यादा तकरार नहीं होगी क्योंकि सबके अपने-अपने प्रभाव क्षेत्र हैं." इस दिशा में की जा रही कोशिशों का लाभ मिलता भी नजर आ रहा है. पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने कहा, "वैसे हम लोग भाजपा के साथ एक मंच से बोलने के खिलाफ हैं. पर जहां जरूरी हुआ, हम उसके साथ तालमेल कर सकते हैं."

विपक्षी नेताओं को एक सूत्र में पिरोने की कोशिशें की जा रही हैं पर दिल मिलना अभी संभव नहीं लगता. शुरू की कोशिशें व्यक्तित्व के टकराव और बुनियादी मतभेदों के कारण असफल हो चुकी हैं. जनता पार्टी से विलय की पिछले साल की कोशिशों में असफल हो चुके देवीलाल मानते हैं, "अभी तक एकता के रास्ते में हर नेता का अहं सबसे बड़ी बाधा है क्योंकि हर आदमी सोचता है कि राजीव गांधी का विकल्प सिर्फ वह हो सकता है."

कर्नाटक के मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े कहते हैं, "विपक्षी दलों की एकता एक मृगतृष्णा है." और जब तक विपक्षी दलों की और खासकर नेतृत्व की विश्वसनीयता नहीं बनती, तब तक यह बात सही भी है. वी.पी. सिंह चेतावनी देते हैं, "हमें मसीहा बनने के रोग से मुक्त होना चाहिए. हर संकट में सही समय पर नेता खुद उभर आते हैं." सबसे पहले वी.पी. सिंह को ही अपने सहयोगियों और विचारधारा के बारे में स्पष्ट करना होगा क्योंकि केंद्रीय व्यक्तित्व होने के कारण उनकी आगे की गतिविधियों से इन पार्टियों की विश्वसनीयता बने-बिगड़ेगी.

—अनीता प्रताप

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आई. डी. बी. आई.

पूँजी-निवेश जमा खाता योजना

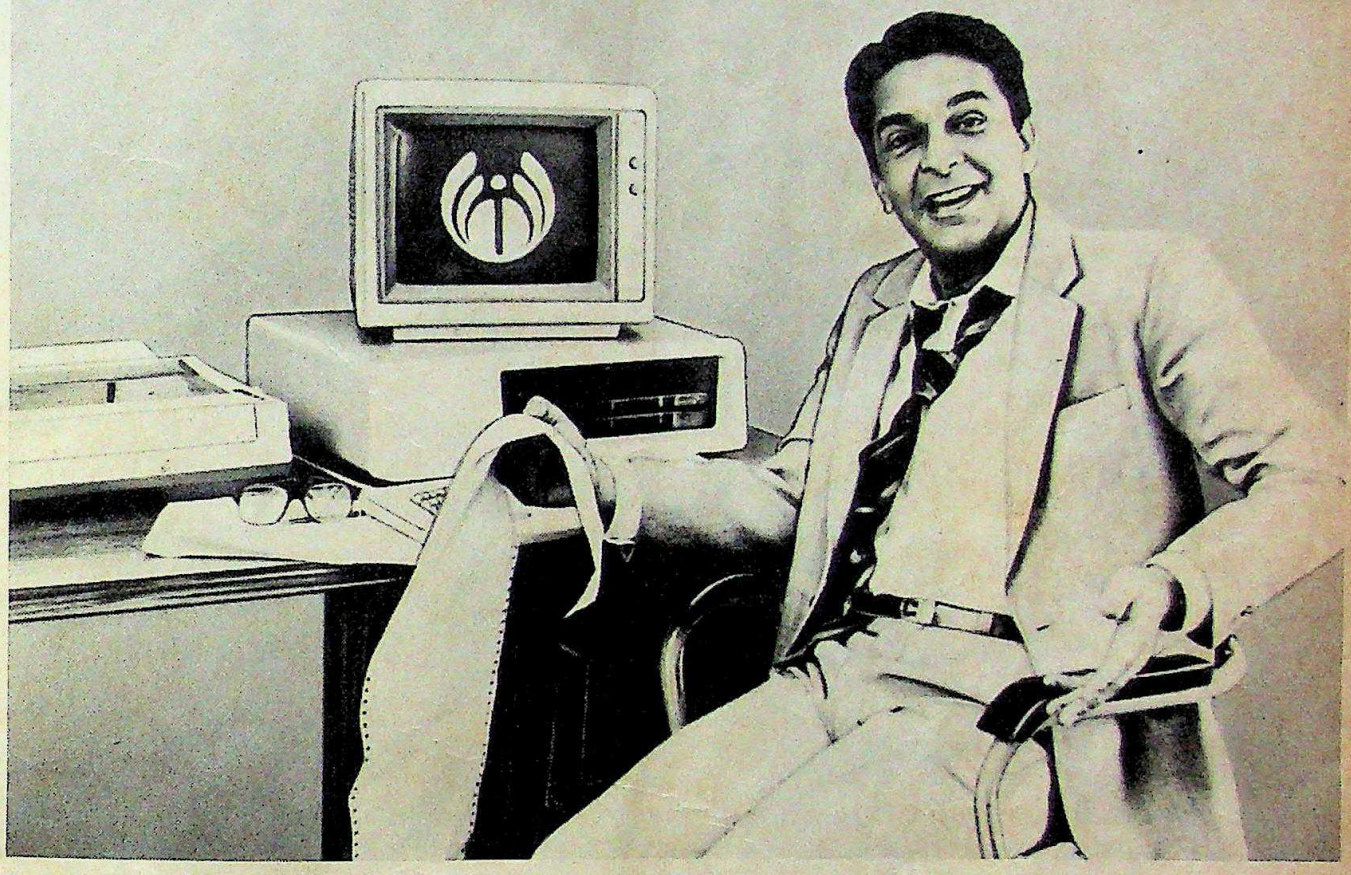

कर बचत योजना

उन सभी कंपनियों, व्यक्तियों, फ़र्मों तथा हिन्दू अविभाजित परिवारों के लिये जिनकी आय आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 32 एबी के अंतर्गत **''व्यापार या व्यवसाय के लाभ और प्राप्तियाँ''** शीर्षक के अधीन कर-योग्य है।

* **इस योजना के अंतर्गत जमाराशि करदाता की कर-योग्य आय के 20% तक कटौती की पात्र होगी।**

* **कर-बचत की पात्रता के लिये आवश्यक है कि कर-दाता लेखा-वर्ष की समाप्ति के 6 मास के अंदर या कर विवरण-पत्र (टैक्स रिटर्न) जमा करने के पूर्व** (जो भी पहले हो) निवेश–राशि जमा कर दे।

* जमा की गयी राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जाएगा। **आय-स्रोत पर कर-कटौती नहीं की जाएगी।** ब्याज की राशि किसी भी प्रकार के उपयोग के लिये मुक्त रूप से खाते से निकाली जा सकती है।

* कर-दाता के व्यापार या व्यवसाय से संबंधित संयंत्र, मशीन, कम्प्यूटर आदि को ख़रीदने या किसी अन्य मान्य प्रयोजन के लिये जमा **मूलधन का आहरण एक साल बाद किया जा सकता है।**

* धारा 32 के अंतर्गत मान्य प्रयोजनों के लिये भी **जमाराशि निकाली जा सकती है।** पूँजी-निवेश के लिये आवेदन पत्र डाक से भेजे जा सकते हैं। साथ में आई.डी.बी.आई. को देय बैंक ड्राफ़्ट या रेखित खाता अदायगी चेक भी होना चाहिए। बाहरी स्टेशनों के चेक भी स्वीकार किये जाते हैं। उनकी वसूली का व्यय आई.डी.बी.आई. द्वारा वहन किया जाएगा। बैंक ड्राफ़्ट के मामले में ड्राफ़्ट ख़रीदने की तारीख़ ही निवेश जमा करने की तारीख़ मानी जाएगी, लेकिन इसके लिये आवश्यक है कि ड्राफ़्ट की तारीख़ से 10 दिन की समुचित अवधि के अंदर ड्राफ़्ट आई.डी.बी.आई. को प्राप्त हो जाए। चेक जमा करने की तारीख़ ही आई.डी.बी.आई. द्वारा निवेश प्राप्त करने की तारीख़ मानी जाएगी।

विस्तृत जानकारी के लिये लिखें :– प्रबंधक,
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) बम्बई 400 021 या आई.डी.बी.आई. के किसी भी कार्यालय से संपर्क करें। हर राज्य में आई. डी. बी. आई. का एक कार्यालय है)। अनुसूचित बैंकों के मुख्य कार्यालयों द्वारा अपनी सभी शाखाओं को पूरी जानकारी भेज दी गयी है।

Sobhagya-B/87 HN

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
जॉली मेकर चैम्बर्स क्र. 2, 225, विनय के शाह मार्ग,
नरीमान प्वाइंट, बम्बई 400 021.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तमिलनाडु

जानकी की अग्निपरीक्षा

लेकिन परदे के पीछे चलती सरकार क्या चल पाएगी?

यह आगे आने वाले घटनाचक्र का संकेत भर था. 64 वर्षीया वैकोम नारायणी जानकी रामचंद्रन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद राज्य सचिवालय के बैठक कक्ष में अपने पहले संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने के लिए कुछ झिझक के साथ प्रवेश किया. प्रभावशाली स्वशासनमंत्री आर.एम. वीरप्पन समेत सातों दूसरे मंत्री भी वहां मौजूद थे. जानकी अपनी जगह पर बैठीं, संकोच से पत्रकारों को नमस्कार किया और उनसे अपनी सरकार को समर्थन देने का आग्रह किया. फिर उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव ए. पद्मनाभन एक महत्वपूर्ण घोषणा करेंगे.

पद्मनाभन बोलने को उठे. उन्होंने बताया कि जानकी ने कुछ ही देर पहले अपनी सरकार का पहला फैसला किया है—राज्य के 10 लाख कर्मचारियों को पोंगल (मकर संक्रांति) के उपहार के रूप में 350-350 रुपए देने का. (खर्च बैठेगा 35 करोड़ रुपए). यह इस बात का सूचक था कि जानकी भी अपने पति की तरह लोकप्रियता बटोरने वाले कार्यक्रम जारी रखेंगी. अखबारवालों ने जो भी सवाल पूछे उनके जवाब दिए वीरप्पन ने.

पिछले पखवाड़े तमिलनाडु में सत्ता संभालने वाली यह सरकार बहुत कुछ महाभारत के एक पात्र शिखंडी की तरह है. पर इस सरकार के सत्ता में आने से कम-से-कम वह दुखद राजनैतिक नाटक तो खत्म हुआ जो एमजीआर को पिछले साल 25 दिसंबर को मरीना बीच पर दफनाने के पहले ही शुरू हो गया था. तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री बनते हुए जैसे ही जानकी ने शपथ ग्रहण की, अन्नाद्रमुक दो टुकड़े हो गई. यह भी संयोग ही है कि दूसरे हिस्से का नेतृत्व भी एक महिला, एमजीआर की प्रिय अभिनेत्री, जयललिता के हाथ ही है.

तमिलनाडु के राज्यपाल सुंदरलाल खुराना ने उनके समर्थन में अगर अपना विवादास्पद फैसला न दिया होता तो जानकी इस लड़ाई में पिट चुकी होतीं. खुराना ने अंतरिम मुख्यमंत्री वी.आर. नेडुनचेडियन (जो एमजीआर मंत्रिमंडल में वित्तमंत्री और दूसरे नंबर पर थे और जो अभी जयललिता के साथ हैं) का एक हफ्ते के अंदर अपना बहुमत साबित करने का अनुरोध ठुकरा दिया. खुराना ने बड़े धड़े की नेता जानकी को सरकार बनाने की अनुमति दी और उन्हें विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए तीन सप्ताह दे दिया.

खुराना ने कहा कि उन्होंने सभी विधायकों को एक फॉर्म दिया था जिस पर उन्हें अपने नेता का नाम लिखकर देना था. जानकी के पक्ष में सबसे ज्यादा विधायकों ने राय जाहिर की जिसकी उन्होंने बाद में पुष्टि भी की.

जिस तेजी से राज्यपाल ने फैसला लिया उससे हरेक को अचरज हुआ. शुरू में उन्होंने नेडुनचेडियन से कहा था कि वे फैसला करने में थोड़ा वक्त लेना चाहते हैं. उन्होंने नेडुनचेडियन को 2 जनवरी की शाम मिलने का समय भी दिया था. पर बाद में वे नहीं मिले. इसके बदले राज्यपाल ने उस समय संवाददाताओं को बुलावा भेजा और जानकी को मुख्यमंत्री नियुक्त करने का एलान कर दिया. ऐसे में, अपने पक्ष में फैसले की आस लगाए जयललिता गुट द्वारा राज्यपाल की आलोचना करना स्वाभाविक ही है. इस गुट ने राज्यपाल की कार्रवाई को गैर-संवैधानिक करार दिया है.

जानकी के शपथ लेने के साथ ही पार्टी बंट गई. नेडुनचेडियन के समर्थक सभी पांच मंत्रियों को सरकार से बाहर रखा गया. लेकिन जयललिता ने भी अन्नाद्रमुक का सबसे महत्वपूर्ण महासचिव का पद हथिया लिया था. उन्होंने संगठन का पूर्ण समर्थन होने का दावा किया. लड़ाई अब पूरे जोरों पर पहुंच चुकी थी. जानकी गुट के सूत्रधार वीरप्पन ने कहा, "हम सभी लोग वी.आर. नेडुनचेडियन का आदर करते हैं. हम सभी लोगों के हाथ भी उन्हीं के पक्ष में उठते पर उन्होंने जिस तरह जानकी अम्मा का नाम घसीटा उससे गड़बड़ हुई. उन्होंने कहा कि

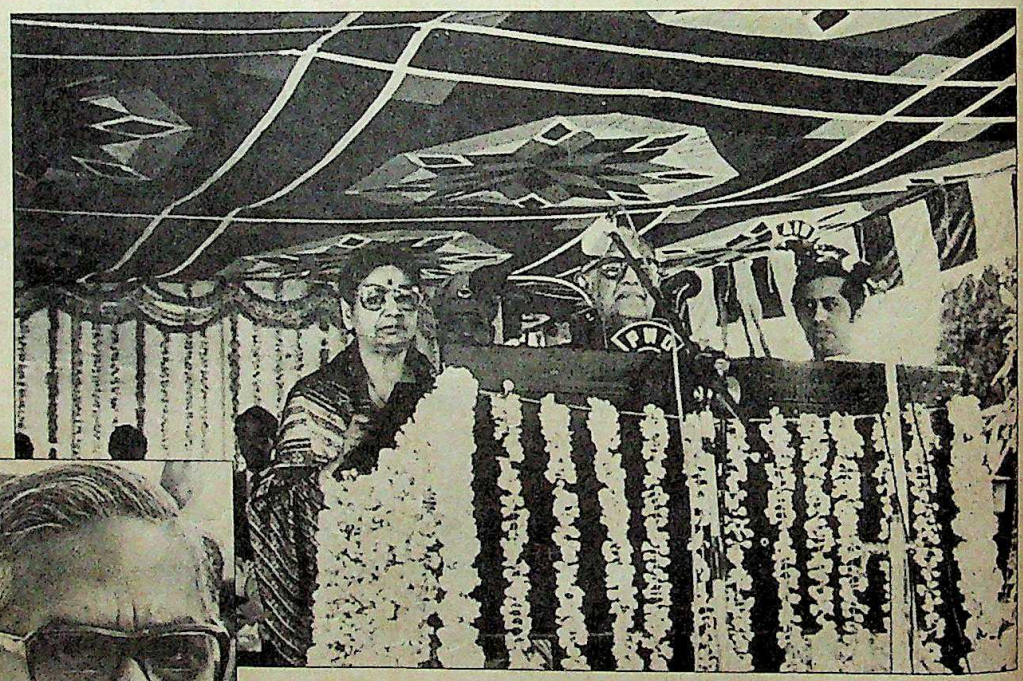

हर किसी के दिमाग में उठ रहा सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जानकी शासन खुद चलाएंगी या पार्टी के दिग्गज वीरप्पन के जरिये

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सभी फोटो : श्याम टेकवानी

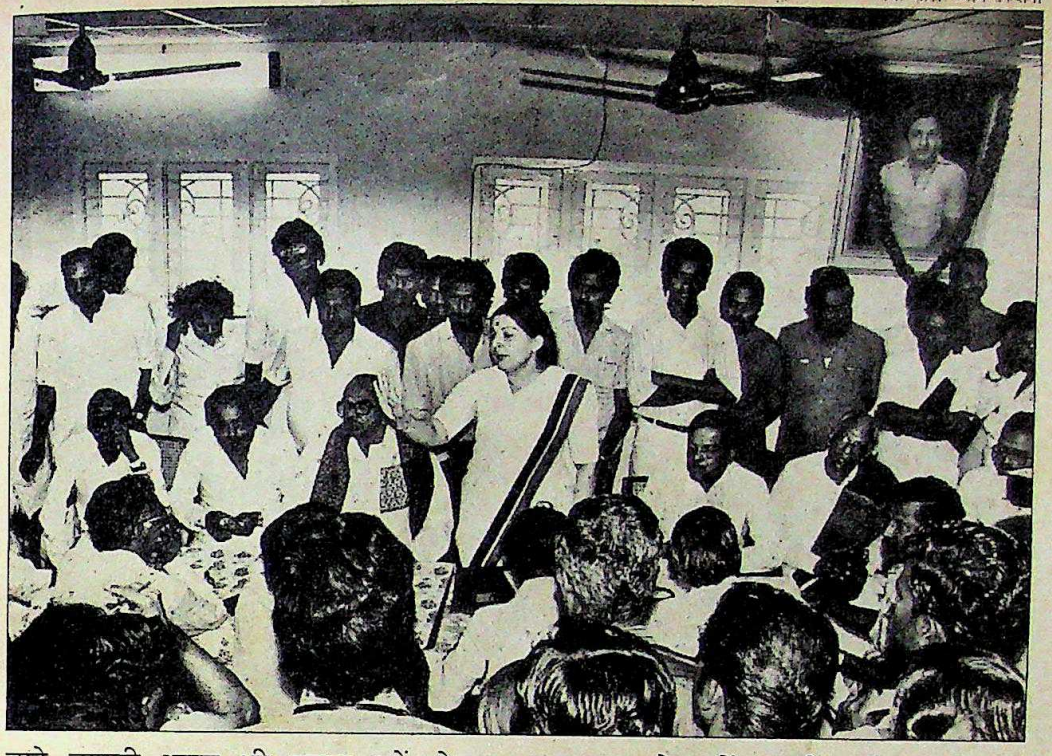

चाहे जानकी अम्मा भी चुनाव लड़ें, वे मुख्यमंत्री पद पर दावा जरूर करेंगे.''

एमजीआर के हर बार इलाज कराने जाने पर मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने वाले 67 वर्षीय नेडुनचेडियन का जवाब था, ''मैंने सिर्फ इतना कहा था कि पुरातची थलैवार (क्रांतिकारी नेता एमजीआर) की 13 सदस्यीय सरकार को 1989 के चुनाव तक मेरे नेतृत्व में ही काम करना चाहिए. पर 24 दिसंबर को ही (जिस दिन एमजीआर मरे) पार्टी के 30 वरिष्ठ नेताओं ने नेता पद के लिए वीरप्पन के नाम का प्रस्ताव रख दिया.''

राजकीय शोक की अवधि खत्म होते ही दोनों गुटों की लड़ाई खुलकर सामने आ गई. शुरुआत वीरप्पन ने ही की. उन्होंने 87 विधायकों को करीब-करीब अपहृत करके मद्रास के एक बढ़िया होटल में हफ्ते भर तक बंद रखा. इसमें रोजाना 70,000 रुपए खर्च आया. दादा लोगों की पहरेदारी में कैद इन विधायकों से परिवार के लोग और पार्टी के पदाधिकारी भी नहीं मिल सकते थे. इनमें से किसी भी विधायक से संपर्क न कर पाना ही नेडुनचेडियन की पहली शिकस्त थी. पर उन्होंने अपने समर्थक 30 विधायकों को तुरंत समेटकर 'भारत दर्शन' पर भेज दिया.

अपने बहुमत की गारंटी कर लेने के बाद वीरप्पन ने जानकी को मुख्यमंत्री बनाने की औपचारिकताएं पूरी करनी शुरू कीं. अन्ना-द्रमुक के उपमहासचिव एस. राघवनंदम और पार्टी संचेतक दुरई गोविंदराजन ने नए नेता का चुनाव करने के लिए विधायकों की बैठक बुलाई. बैठक के बाद सात मंत्रियों समेत ये

पत्रकार सम्मेलन में जयललिता व नेडुनचेडियनः स्पष्ट विभाजन

87 विधायक चार डीलक्स बसों और 20 कारों में राज्यपाल से मिलने राजभवन गए.

जयललिता गुट भी मैदान से नहीं भागा. तमिलनाडु में हालांकि तिजोरियों के मुंह वीरप्पन गुट के पक्ष में खुले हुए थे पर कहा जाता है कि बंगलूर का एक उद्योगपति भी जयललिता के गुट की मदद को आगे आया. इस गुट ने अपने 32 विधायकों को मद्रास के एक पांच सितारा होटल के 18 कमरों में पांच दिनों तक रखा. उन्होंने वीरप्पन गुट की बैठक को गैरकानूनी बताया और कानूनी जीत पाने के लिए जयललिता को पार्टी का महासचिव नियुक्त किया जिससे वे विधायक दल की बैठक बुलाने की अधिकारी बन जाएं. जयललिता का दावा है कि वे 24 में से 14 जिला सचिवों की सहमति से महासचिव चुनी गई हैं. महासचिव की हैसियत से उन्होंने जो बैठक बुलाई उसमें नेडुनचेडियन नेता चुने गए. जयललिता कहती हैं, ''एमजीआर के समय में सिर्फ महासचिव ही पार्टी की बैठकें बुलाता था. जब वे मरे तो पार्टी के महा-सचिव थे. यह पद खाली हो गया. इसलिए विधायक दल की बैठक बुलाने से पहले नए महासचिव का चुनाव होना चाहिए था.''

दोनों ही गुट कहते हैं कि उनके विरोधी गुट की बैठक अवैध थी. पर राज्यपाल खुराना ने वीरप्पन/जानकी गुट की बैठक को वैध करार दिया. जयललिता ने तुरंत राज्यपाल खुराना ने वीरप्पन/जानकी गुट की बैठक को वैध करार दिया. जयललिता ने तुरंत राज्यपाल पर 'पक्षपात' का आरोप लगाया. वीरप्पन द्वारा राज्यपाल के आगे विधायकों की परेड कराने पर नेडुनचेडियन ने कहा, ''अगर राजभवन मंत्रियों को परेड करने का आदेश देने का मैदान बन जाए तो वह दिन दूर नहीं जब विश्वास प्रस्ताव भी राज-भवन में ही पास हुआ करेंगे.''

सत्तारूढ़ अन्नाद्रमुक की ताकत में कमी आने से तमिलनाडु में राजनैतिक खेल की बागडोर अब इंका के हाथ में आ गई है. मुख्य-मंत्री के रूप में जानकी के भविष्य का फैसला 23 जनवरी से पहले विधानसभा की बैठक में होगा. उन्हें 235 सदस्यों के सदन में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है. जय-ललिता गुट के 30 विधायकों के उनके समर्थन में आने या इंका के 64 विधायकों के समर्थन से ही उनकी सरकार टिक सकती है. जयललिता गुट पहले ही दल में शांति कायम करने की जानकी की अपील को ठुकरा चुका है. इसलिए 1967 के बाद पहली बार तमिलनाडु में किसी सरकार का चल पाना इंका के समर्थन पर निर्भर हो उठा है. और जैसी कि उम्मीद थी, वीरप्पन ने तुरंत दिल्ली से दोस्ती गांठने की शुरुआत कर दी. सबसे पहले उन्होंने एमजीआर को श्रद्धां-जलि अर्पित करने के लिए राजीव गांधी का आभार प्रदर्शित किया. फिर कुछ मंत्रियों ने केंद्रीय मंत्रियों—बूटा सिंह और नरसिंहराव —को फोन करके भरोसा दिलाया कि वे भारत-श्रीलंका समझौते को लागू करने में पूरा सहयोग देने को तैयार हैं.

इंका ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं. वह ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहती जिससे तमिलनाडु की राजनीति की बागडोर द्रमुक नेता करुणानिधि के हाथ चली जाए. जानकी को खुला समर्थन देना आत्मघाती होगा क्योंकि उन्हें अभी जनता तथा पार्टी में अपनी लोकप्रियता साबित करनी है. अगर जानकी को समर्थन देने के कारण पार्टी की जनता से दूरी बढ़ती है तो इंका की जड़ें ही उखड़ जाएंगी. फिर, वीरप्पन गुट में ऐसे कई विधायक हैं जो इंका और श्रीलंका समझौते के विरोधी हैं. वैसे जानकी ने भरोसा दिलाया है कि उनकी सरकार समझौते का समर्थन करेगी पर समझौते के खिलाफ होने वाले किसी आंदोलन को दबाने की क्षमता उनमें नहीं दिखती. उधर जयललिता के पास विधायकों का बहुमत भले ही न हो पर पार्टी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कार्यकर्ताओं और आम लोगों में वे लोकप्रिय हैं. इसलिए अधिकांश इंकाई दोनों गुटों से समान दूरी रखने के पक्ष में हैं.

इसी बीच जयललिता ने राज्य भर में जनसभाएं करने की योजना बनाई है. वीरप्पन ने इसकी जवाबी योजना बनाई है. जयललिता कहती हैं, "जब 1972 में करुणानिधि ने एमजीआर को पार्टी से निकाल दिया था तो उनके पास विधायक तो रहे पर एमजीआर पार्टी कार्यकर्ताओं को अपने साथ ले गए. यही बात अब दोहराई जा रही है." और पिछले पखवाड़े तमिलनाडु में यही सवाल सबसे अहम था कि क्या इतिहास अपने को दोहराने जा रहा है.

—एस.एच. वेंकटरमनी

जानकी रामचंद्रन

भाग्य की धनी

चौंसठ साल की वैकोम नारायणी जानकी के जीवन में कई विसंगतियां हैं. वे खुद ब्राह्मण हैं और तमिलनाडु में सत्तारूढ़ पार्टी यानी अन्नाद्रमुक का गठन ब्राह्मण विरोधी आंदोलन के आधार पर हुआ है. वे मलयाली हैं, एक ऐसे राज्य में जहां के लोग अपनी पहचान—तमिल होने—के प्रति बहुत संवेदनशील हैं. वे महिला हैं और तमिल समाज घनघोर रूप से रूढ़िवादी. लेकिन एक खासियत है जिसके कारण अपने प्रतिस्पर्धियों से उनका हाथ हमेशा ऊपर रहा है. वे पूरे 34 साल तक तमिलनाडु के करिश्माई मुख्यमंत्री मरुदर गोपाल मेनन रामचंद्रन की अर्द्धांगिनी रही हैं.

तेजी से घूमते घटनाचक्र ने जानकी को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद पर ला बिठाया है. लेकिन इससे पहले भी उनकी तकदीर कई अविश्वसनीय मोड़ काट चुकी है. जानकी का जन्म केरल के वैकोम गांव में पी.आर. राजगोपाल अय्यर के यहां हुआ था. गरीबी के कारण उनकी शिक्षा प्राइमरी स्कूल से ज्यादा नहीं हो पाई. लेकिन परिवार का दारिद्र्य नृत्य और संगीत की शिक्षा लेने और फिर फिल्मों में जाने में बाधक नहीं बन पाया. तब सिने जगत में एक गणपति भट हुआ करते थे, जानकी ने उनसे ब्याह रचा लिया. एमजीआर के साथ तो वे 1948 में पहली बार 'मोहिनी' नाम की फिल्म में आईं. एमजीआर के साथ कुछ और फिल्में करने के बाद जानकी ने उनसे विवाह कर लिया और फिर फिल्मों को तिलांजलि दे दी.

एमजीआर के अन्नाद्रमुक का गठन करने के कुछ दिन बाद तक वे पति के साथ प्रदर्शनों और आंदोलनों में शामिल होती रहीं लेकिन राजनीति में उनकी भूमिका गौण ही रही. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. अक्तूबर 1984 में जब एमजीआर को पक्षाघात का दौरा पड़ा और उन्हें बात करने में कठिनाई होने लगी तो हर काम के लिए वे जानकी पर ही निर्भर रहने लगे. पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि "उन दिनों वे एमजीआर, सरकार और दल के बीच एकमात्र संपर्क-सूत्र थीं." कई बार वे एमजीआर की ओर से अधिकारियों और दल के नेताओं को निर्देश भी दिया करती थीं. पूर्व श्रम राज्यमंत्री के.ए. कृष्णास्वामी बताते हैं कि "जब भी एमजीआर मंत्रियों और दल के लोगों पर बिगड़ते, जानकी मध्यस्थ की भूमिका निभातीं."

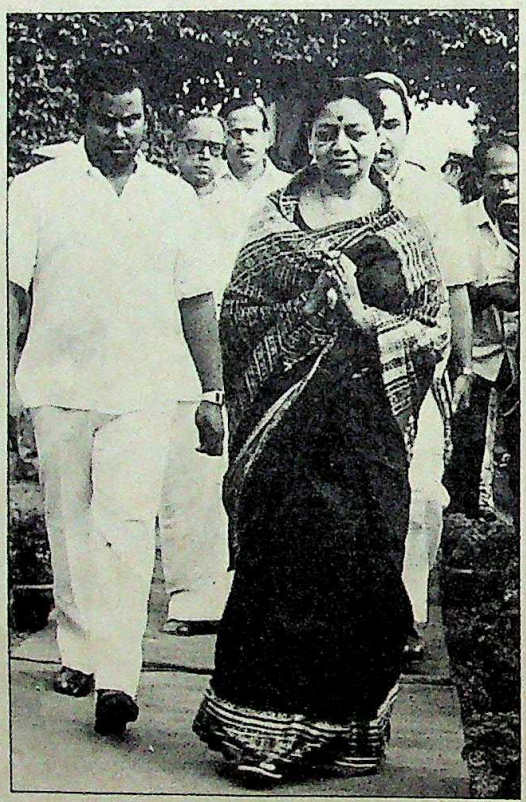

जानकी: कसौटी पर

पर उनका हस्तक्षेप लोगों के गले आसानी से नहीं उतरा. 1985 के शुरू में ही जयललिता जयराम ने, जो अब खुद के अन्नाद्रमुक का महासचिव होने का दावा करती हैं, जानकी को एमजीआर की आड़ में सत्ता पर कब्जा किए बैठे चौगुटे का सरगना बताया था. उनकी राजनैतिक महत्वाकांक्षा से वाकिफ हो चुकी जानकी उनके पर कतर देना चाहती थीं. जब एमजीआर अमेरिका में अस्पताल में भर्ती थे तब भी जानकी यहां मौजूद अपने समर्थकों से लगातार संपर्क बनाए हुई थीं ताकि जयललिता एमजीआर की अनुपस्थिति का लाभ उठाते हुए अपना प्रभाव न बढ़ा लें. एमजीआर ने जयललिता और अपनी पत्नी की राजनैतिक भूमिका के बारे में पिछले वर्ष एक निर्देश जारी किया था कि अधिकारी उनकी पत्नी या परिवार के किसी और सदस्य से कोई वास्ता न रखें. जानकी तीन वर्षों से सरकारी फैसलों में दखल देती रही थीं सो वे एकदम अलग होने को तैयार नहीं थीं.

लेकिन जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो हर किसी के दिमाग में यही सवाल घूम रहा था कि क्या वे खुद को आर.एन. वीरप्पन के हाथ की कठपुतली बनने से रोक पाएंगी? आशंका निराधार नहीं है. मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने जो पत्रकार सम्मेलन किया उसमें 60 लाख कर्मचारियों को पोंगल के उपहार के रूप में 350-350 रुपए देने की घोषणा के बाद जो सवाल पूछे गए उनके जवाब वीरप्पन ने ही दिए. 35 करोड़ रुपए के खर्चे वाली यह घोषणा भी मुख्य सचिव ए. पद्मनाभन ने की. और बाद में जब जानकी बाहर निकलीं तो यही लग रहा था कि चाबी वीरप्पन के हाथ है.

पर कई लोगों का मानना है कि जानकी को कोई बुद्धू नहीं बना सकता. तमिल पाक्षिक 'तुगलक' के संपादक चो रामस्वामी कहते हैं, "आखिर में हो सकता है कि वे वीरप्पन के हाथ की कठपुतली साबित न हों." और उनके समर्थकों का मानना है कि उनमें नेता के सारे गुण हैं. अन्नाद्रमुक सांसद और तमिल साप्ताहिक 'थै' के संपादक वी.जॉन कहते हैं, "उनकी संभावनाओं का भंडार धीरे-धीरे बाहर आएगा."

—एस.एच. वेंकटरमनी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गर्भजल परीक्षण

अनुकरणीय निर्णय

सरकार जनमत के आगे झुकी

महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने पिछले साल के अंतिम दिन एक ऐसा फैसला किया जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं. फैसले के अनुसार सरकार एक नया विधेयक ला रही है जिसमें गर्भजल परीक्षण पर रोक लगाने की व्यवस्था है. ऐसी रोक लगाने वाला यह पहला राज्य होगा. बताया जाता है कि इस परीक्षण व्यवस्था के दुरुपयोग से 1978 और 1983 के बीच देश भर में गर्भपात के ऐसे 78,000 मामले हुए जिनमें लड़की के जन्म की संभावना थी.

असल में ये परीक्षण आनुवंशिक विकृतियों, वंशानुगत रोगों तथा गुणसूत्रों में दोषों का पता लगाने के लिए किए जाते हैं. लेकिन चूंकि इसके द्वारा गर्भ में पल रहे शिशु के लिंग के बारे में भी जाना जा सकता है, पुरुष प्रधान समाज में मक्कार डॉक्टरों को लाभ उठाने का अच्छा अवसर मिल गया. तभी सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा शोधकर्ताओं ने इन परीक्षणों को 'कन्या भ्रूण हत्या' का नाम दिया है.

गर्भपात के ऐसे 1000 मामलों के एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि इनमें 97 प्रतिशत में लड़की के जन्म की संभावना थी. दूसरा सबसे आश्चर्यजनक निष्कर्ष तो 1982 में बंबई के वीमेंस सेंटर के सर्वेक्षण से मिला—गर्भपात के 8000 में से 7,999 मामलों में कन्या के जन्म लेने की संभावना थी. वैसे इन आंकड़ों को चुनौती दी गई है.

सामाजिक लाभ हासिल करने की इस विकृत मानसिकता के संभावित खतरे भी हैं. गर्भजल परीक्षणों से भ्रूण और बीजांडासन (प्लेसेंटा) तो नष्ट होते ही हैं, अपने आप गर्भपात या समय पूर्व प्रसव की आशंका भी रहती है. बंबई के श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी फार्मेसी कॉलेज के डॉ. आर.पी. रवीद्र के अनुसार इस परीक्षण से कूल्हों के खिसकने तथा सांस की बीमारी की भी संभावना रहती है.

महाराष्ट्र के जन स्वास्थ्य विभाग के सचिव डी.टी. जोसफ बताते हैं कि नए विधेयक से इन परीक्षणों के दुरुपयोग पर रोक लगेगी. सिर्फ सरकारी तथा स्थानीय निकायों के अधीन चल रहे अस्पतालों तथा मान्यता प्राप्त मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूटों को ही इन परीक्षणों की छूट होगी और वह भी सिर्फ आनुवंशिक दोषों को जानने के लिए ही. और ये परीक्षण 35 वर्ष की आयु से ऊपर की वे महिलाएं ही करा सकेंगी जिनके गर्भधारण में देरी होती हो या जिन्हें आनुवंशिक या प्रसूति संबंधी गड़बड़ियां हों.

असल में, 1977 से ही इन परीक्षणों का चलन बढ़ा. बंबई में ऐसे परीक्षण करने वाले 258 प्राइवेट तथा 16 सरकारी मान्यता प्राप्त क्लीनिक हैं. इस परीक्षण के लिए किसी तरह की सरकारी अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती. फिर यह परीक्षण सस्ते में (150 रुपए से 500 रुपए के बीच) हो जाता है. एक क्लीनिक ने विज्ञापन किया कि यह दहेज का सस्ता विकल्प है.

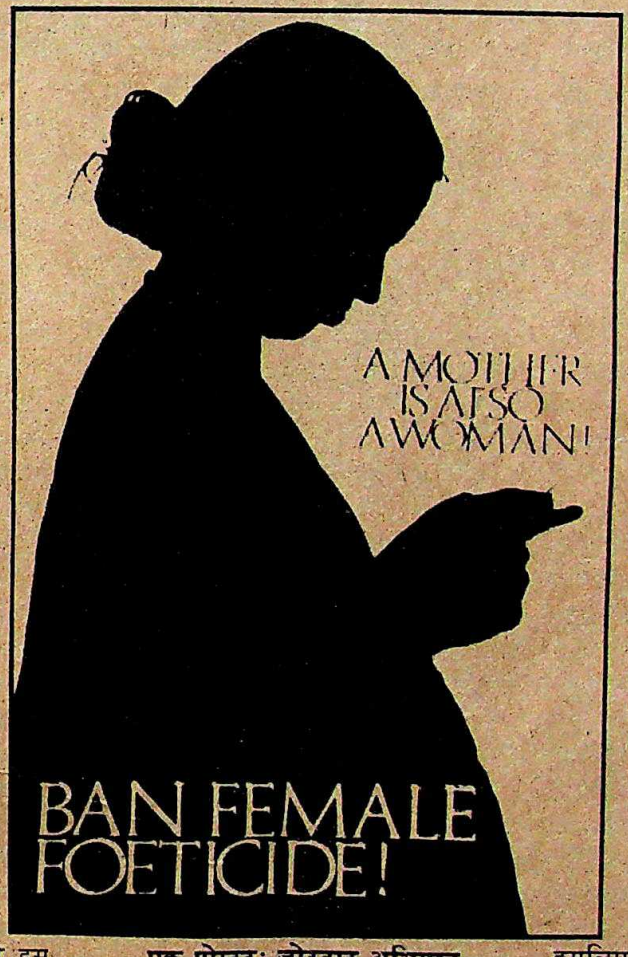

एक पोस्टर: जोरदार अभियान

मृणाल गोरे ने इंका के सरयू ठाकुर और श्याम वानखेड़े के साथ मिलकर महाराष्ट्र विधानसभा में 1986 में एक निजी विधेयक पेश किया था. उन्होंने इसे सरकार के इस फायदे पर वापस ले लिया कि वह ऐसा ही विधेयक पेश करेगी. गोरे कहती हैं, "मेरे विधेयक को सदन में काफी समर्थन मिला. विधेयक के लिए मैं सरकार की आभारी हूं, हालांकि अभी मैंने उसे देखा नहीं है."

लेकिन इन परीक्षणों के आलोचकों का मानना है कि विधेयक ही पर्याप्त नहीं है. एक शोधकर्ता मनीष गुप्ते का कहना है, "कुछ आनुवंशिक रोग सेक्स से जुड़े होते हैं. इसलिए अगर आप ऐसे रोगों के बारे में जानना चाहते हैं तो अनायास ही आप शिशु के लिंग के बारे में न चाहते हुए भी जान जाते हैं." गुप्ते उस सरकारी समिति के भी सदस्य हैं जिसे विधेयक का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. यह विधेयक डॉक्टरों को गर्भ में पल रहे शिशु का लिंग अभिभावकों को बताने पर रोक लगाता है. लेकिन सेक्स की पूर्व जानकारी देने वाले कुछ परीक्षण, जैसे एरिक्सन परीक्षण इस विधेयक के दायरे में नहीं आते.

कई नारी मुक्ति दलों ने इन परीक्षणों का सख्त विरोध किया है और इन पर रोक लगाने की मांग की है. धुले की सामाजिक कार्यकर्ता सोनल शुक्ल कहती हैं, "जब तक परीक्षणों की अनुमति रहेगी. इनका दुरुपयोग भी जारी रहेगा." लेकिन जन स्वास्थ्य विभाग के सचिव जोसफ का कहना है, "लोगों को चिकित्सा की वे सुविधाएं मुहैया करानी होंगी जिनसे वंशानुगत रोगों पर अंकुश लगाया जा सके."

लेकिन एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि 84 प्रतिशत स्त्री रोग विशेषज्ञ ऐसा परीक्षण करते रहे हैं. एक विशेषज्ञ ने शिकायत की, "अगर आप प्रशिक्षित विशेषज्ञ को इस परीक्षण से रोकेंगे तो महिलाएं नीम हकीमों के पास जाएंगी."

इस मामले से नैतिक दुविधाएं भी जुड़ी हैं अगर कोई गर्भपात इसलिए नाजायज है कि गर्भ में कन्या है, तो किसी अपाहिज बच्चे को जन्म देने से रोकने का अधिकार भी समाज को क्यों हो? फिर क्या यह प्रतिबंध अनचाहे शिशु के गर्भपात करवाने के अधिकार के माकूल है?

बहरहाल, इन परीक्षणों के खिलाफ आवाज उठाने वाले कार्यकर्ताओं को राज्य मंत्रिमंडल के फैसले से एहसास हो गया है कि अगर कोई सरकार प्रगतिशील दिखना चाहती है तो उसे संगठित जनमत के आगे बाध्य होकर काम करने पर मजबूर किया जा सकता है.

—सलिल त्रिपाठी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दिल्ली

मैदान छोड़ दिया

चुनाव स्थगन से इंकाई परेशान

महानगर परिषद और दिल्ली नगर निगम के चुनावों के लिए राजधानी का राजनैतिक माहौल गरमा ही रहा था कि राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर चुनाव एक साल के लिए स्थगित कर दिए. कार्रवाई जिस तेजी से हुई उससे संदेह ही उपजा. विपक्ष ने आरोप लगाया कि इंका मतदाताओं का सामना करने से कतरा रही है.

27 दिसंबर चुनाव घोषणा की आखिरी तारीख थी. दिल्ली प्रशासन ने 1987 के शुरू में ही इस वायदे के साथ नगर निगम का कार्यकाल बढ़ा दिया था कि उसके चुनाव अब महानगर परिषद के साथ ही कराए जाएंगे. और फिर महीने के शुरू में परिषद ने कर-रहित मुनाफे के बजट की घोषणा भी की थी जिससे इन अटकलों को बल मिला कि चुनाव बस होने ही वाले हैं. लेकिन 24 दिसंबर को उन्हें स्थगित करने का एलान कर दिया गया.

प्रदेश भाजपा के नेता मदनलाल खुराना ने गुस्से में कहा, "यह जनता के लोकतंत्रीय अधिकारों पर प्रहार है." विरोध प्रकट करने के लिए वे राजधानी की सड़कों पर निकल आए और इंका की 'नाकामियों का भंडाफोड़' करने के लिए उन्होंने 150 किलोमीटर से अधिक की पदयात्रा की. अनेक विपक्षी सदस्यों ने भी इस फैसले के विरोध में गिरफ्तारियां दीं.

इंका आकाओं के फैसले से जहां पार्टी को दम लेने का कुछ वक्त मिला है, वहीं इससे दिल्ली के नेताओं को भारी परेशानी भी झेलनी पड़ी है. कुछ ही समय पहले दिल्ली प्रदेश इंका अध्यक्ष ताजदार बाबर ने चुनाव स्थगित किए जाने की खुराना की आशंकाओं को बेबुनियाद करार दिया था. मुख्य कार्यकारी पार्षद जगप्रवेश चंद्र ने भी 'चुनाव समय पर करवाने' का वायदा किया था. चुनाव आयुक्त के दफ्तर से तो मतपत्र छापने के आदेश भी दिए जा चुके थे.

चुनाव स्थगित किए जाने के साथ ही नगर निगम का कार्यकाल बढ़ाकर छह साल कर दिया गया. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ. सदन में भाजपा के नेता शांति देसाई ने इसकी निंदा की, "यदि सरकार का बस चले तो वह चुनाव ही न करवाए."

इसके लिए बहाना यह ढूंढ़ा गया कि

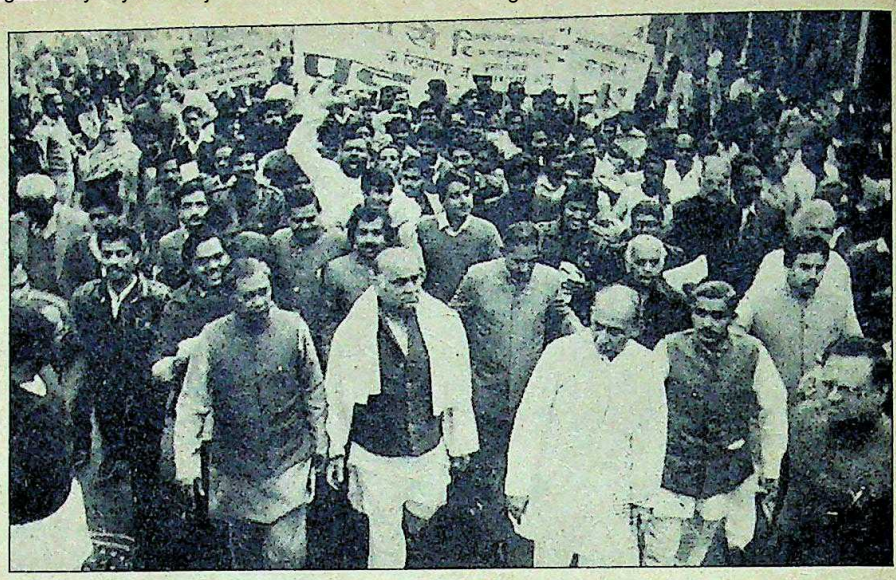

भाजपा का प्रदर्शनः तगड़ा विरोध

केंद्रशासित प्रदेश में प्रशासन तंत्र चूंकि अराजक स्थिति में है इसलिए उसके पुनर्गठन की जरूरत है. चुनाव स्थगन के साथ ही जस्टिस आर.एस. सरकारिया की अगुआई में एक उच्चस्तरीय समिति की नियुक्ति की भी घोषणा की गई जो दिल्ली के लिए प्रशासन के एक नए ढांचे का प्रारूप तैयार करेगी. इस समिति में पूर्व शहरी विकास सचिव रमेश चंद्र और गृहमंत्रालय के सलाहकार एस. बालकृष्णन भी लिए गए हैं. इरादा, जाहिर है कि केंद्रशासित प्रदेश को राज्य का दर्जा देने का है.

वास्तव में दिल्ली को राज्य का दर्जा दिए जाने का आधार भी है. प्रशासन की कई इकाइयों—दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका और छावनी बोर्ड के निकम्मेपन के चलते राजधानी के 70 लाख लोग काफी अरसे से नाराज हैं.

जिनका आम लोगों से वास्ता पड़ता है उन निकायों की हालत भी कोई अच्छी नहीं है. दिल्ली विकास प्राधिकरण को 1986-87 में ही 500 करोड़ रुपए से अधिक का घाटा हो चुका है और वह शहर का नियोजित विकास करने में बुरी तरह नाकाम रहा है. दिल्ली परिवहन निगम भी उसी दिशा में बढ़ रहा है. पिछले साल एकमुश्त ढाई गुना किराए बढ़ाने के बावजूद उसका कुल घाटा 1,000 करोड़ रुपए से ऊपर जा चुका है. यह अराजक स्थिति ही दिल्ली को राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग का मुख्य आधार है.

दिल्ली में पार्टी मामलों के प्रभारी, इंका महासचिव अॅस्कर फर्नांडीस कहते हैं, "विपक्ष भी तो दिल्ली को राज्य बनाने की मांग करता आया है. इसके लिए अब जब ठोस कदम उठाया गया तो वे ही इसके खिलाफ प्रचार करते फिर रहे हैं." पर विपक्षी नेता इस बात का खंडन करते हैं. खुराना कहते हैं, "राज्य बनाए जाने की मांग नई नहीं है. सत्तारूढ़ पार्टी ने भी अपने पिछले तीन घोषणा-पत्रों में इसका वायदा किया था. पांच साल सत्ता भोगने के बाद उनकी नींद अभी कैसे खुली है?"

इंका आलाकमान को शायद अपनी दिल्ली इकाई पर पूरा भरोसा नहीं था. चुनाव पास आते-आते उसने 56 ब्लॉकों में पार्टी बैठकों के पर्यवेक्षण के लिए राज्यसभा के सात सदस्यों की एक समिति मुकर्रर कर दी थी. दिसंबर अंत तक हुई 44 बैठकों में स्थानीय सांसद, महानगर पार्षद और प्रदेश इंका पदाधिकारी मौजूद थे. मगर पार्टी में चल रही ज़बरदस्त खींचातानी पर काबू नहीं पाया जा सका.

प्रदेश इंका के भीतर नए जोड़तोड़ होते रहे. पार्टी के दिग्गज और संसदीय कार्यमंत्री हरकिशनलाल भगत और केंद्रीय शहरी उड्डयन राज्यमंत्री जगदीश टाइटलर में सुलह हो गई. पिछले चुनावों में वे एक दूसरे को फूटी आंखों नहीं सुहाते थे, पर चुनाव स्थगित कराने के मुद्दे पर वे एक हो गए. दिल्ली की राजनीति में गोटियां बिठा रहे संचारमंत्री अर्जुन सिंह ने भी तत्काल चुनावों का विरोध किया. इस बीच बेगम बाबर के भगत से मतभेद हो गए. उन्होंने एक तरफ रक्षामंत्री कृष्णचंद्र पंत और अर्जुन सिंह तथा दूसरी तरफ भगत लॉबी के बीच संतुलन बिठाने की कोशिश की थी.

इंका राजीव सरकार को घेरे विवादों के ठंडा पड़ने का इंतजार करना चाहती है. पर भाजपा द्वारा चुनाव स्थगन के विरोध में 'आंदोलन वर्ष' की घोषणा से इंका के सारे दांव उलटे पड़ सकते हैं. —पंकज पचौरी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बिहार

गद्दी बचाने की तिकड़म

असंतोष और खस्ताहाल अर्थव्यवस्था के बावजूद दुबे बरकरार

सब तरफ पार्टियों और समारोहों की धूम थी. हजार गेंदे और गुलाबों से गुंथे एक हजार हार, 40 पौंड का विशाल केक और सबसे बढकर जोशीले भाषण. यह सारा आयोजन बिहार की दुबे सरकार के सत्ता में एक हजार दिन पूरे करने के उपलक्ष्य में था. इस तमाशे की रही सही कमी पूरी की इंका के तिकड़मी कोषाध्यक्ष सीताराम केसरी ने, जो कुछ समय पहले तक दुबे की आंख की किरकिरी बने हुए थे. नाटकीय अंदाज में वे हाथ जोड़े आए और 'राजनैतिक संत' दुबे के चरणस्पर्श करके उन्होंने सबको चौंका दिया. दुबे 'बाबा' ने भी केसरी को अपना 'आशीर्वाद' देकर उनका अभिवादन स्वीकार किया. हालांकि यह सारा आडंबर यही सिद्ध करने के लिए था कि दिल्ली और पटना में अपने खिलाफ बढ़ते असंतोष के बावजूद दुबे मजबूती से कुर्सी पर जमे हुए हैं. एक समारोह में उन्होंने गरजते हुए सफाई दी कि "मैं खुद ऐसी पार्टियों और आत्मश्लाघा के विरुद्ध हूं लेकिन अब यह जरूरी हो चला है, क्योंकि मैं उन आलोचकों का मुंह बंद करना चाहता हूं जो पहले दिन से ही मेरी सरकार के दिन गिनते आ रहे थे."

लेकिन दुबे और उनके समर्थकों द्वारा ओढ़ा गया निश्चितता और संतुष्टि का यह मुखौटा उनके डर को छिपाए नहीं रख पाया. लोगों के लिए हैरानी की बड़ी बात यह रही कि दुबे ने अचानक ही 1988-89 का बजट पेश करने का फैसला कर लिया. पार्टी सूत्रों के अनुसार इस बेमौसमी फैसले ने राज्यपाल पी. वेंकटसुबैया को भी सकते में डाल दिया और उन्होंने एक बार तो इस संक्षिप्त बजट अधिवेशन के लिए जारी की जाने वाली अधिसूचना पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया. लेकिन दुबे अपनी जिद पर अड़े रहे. उनकी दलील थी, "आप इसे भले ही अस्थायी बजट कह लें पर राज्य में आई इस सदी की अभूतपूर्व बाढ़ के कारण यह बहुत जरूरी हो चुका है."

पर 8 जनवरी को विधानसभा का अधिवेशन भारी हंगामे के बीच शुरू हुआ.विपक्षी सदस्यों हाथों में गेहूं की बालियां लिये राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान पूरे समय नारेबाजी करते रहे. उनका आरोप था कि किसानों को घटिया बीज और खाद दिए जाने के कारण समय से पहले ही गेहूं की बाली निकल आई है. और शोर-शराबे के दौरान इंका सदस्य चुपचाप बैठे रहे.

सिर मुंडाते ही ओले पड़ने से दुबे कहां तक अस्थायी बजट की नैया पार करा पाएंगे, यह

एक तो आर्थिक संकट और उस पर पार्टी असंतुष्टों की चुनौतियां. इन दो कारणों से मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे की स्थिति नाजुक हो गई है

तो समय ही बताएगा. मगर दुबे ने 'इंडिया टुडे' को बताया कि जनवरी में अस्थायी बजट पेश करके सदन की अनुमति लेने का लाभ यह होगा कि 1988-89 की वित्तीय आवश्यकताओं का समय रहते फैसला हो जाएगा और वर्ष भर की योजनाओं पर पहले से ही कार्रवाई के लिए सरकार को तैयार रखा जा सकेगा. दुबे की दृष्टि में यकीनन यह एक नया विचार है पर उनके आलोचक इसे वित्त प्रबंध के मामलों में दुबे की जानकारी बहुत कमजोर होने का प्रमाण बता रहे हैं.

इन आलोचकों की सूची में प्रमुख स्थान रखने वाले जगन्नाथ मिश्र की प्रतिक्रिया स्पष्ट और तीखी थी, "यह सरासर मूर्खता है. बिना योजना की मंजूरी के भला कोई सरकार कैसे पहले से बजट पेश कर सकती है? दुबे भले ही ऐसा करके इतिहास रचने जा रहे हों पर उन्हें यह भी समझ लेना चाहिए कि उनका यह कदम राज्य को और अधिक बरबाद कर सकता है."

'अस्थायी बजट' पेश करने के मामले में दुबे सचमुच इतिहास रच रहे हैं क्योंकि ऐसा कदम उठाने वाले वे पहले मुख्यमंत्री हैं. हालांकि तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रशेखर सिंह ने भी जनवरी 1985 में बजट पेश किया था लेकिन तब अप्रैल में होने वाले आम चुनावों को देखते हुए ऐसा करना जरूरी हो गया था. आर्थिक विशेषज्ञों और दुबे के आलोचकों ने अपनी टिप्पणियों में उनका ध्यान इस ओर खींचा है कि योजना खर्चों के लिए योजना को सदन की अनुमति मिलना बहुत जरूरी है. ऐसे में दुबे यदि यह आशा लगाए हुए हैं कि बजट के धन का वे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं तो ऐसा केवल गैर-योजना मदों में ही संभव होगा. इस खर्च के लिए अनुमति लेना जरूरी नहीं है.

अस्थायी बजट के कानूनी पहलू को छोड़ भी दिया जाए तो भी एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि 300 करोड़ रुपए से भी अधिक के बजट घाटे को देखते हुए योजना आयोग ने इस बात का विरोध किया था कि बिहार के इस साल के 1500 करोड़ के मुकाबले अगले साल का उसका बजट 1650 करोड़ रुपए रखा जाए. उधर दुबे लगातार दावा करते आ रहे हैं कि बिना अधिक पैसा खर्च किए उनकी सरकार सबसे ज्यादा तेजी से आर्थिक विकास कर रही है (देखें इंडिया टुडे 15 दिसंबर, 1987) इसका सारा श्रेय वे अपनी आर्थिक प्रबंध नीतियों को देते हैं.

पिछले दिसंबर में जब बिहार सरकार के अधिकारियों ने योजना के बारे में बातचीत के सिलसिले में नई दिल्ली के बिहार भवन को मेले जैसा रूप दे दिया था तब योजना आयोग की ओर से उन्हें स्पष्ट कर दिया गया था कि अपने वित्त प्रबंध के सभी दावों के बावजूद बिहार सरकार 1650 करोड़ की योजना नहीं चला पाएगी. राज्य सरकार के 'शानदार वित्त प्रबंध' के दावे भी काफी रोचक हैं. सचिवालय सूत्रों के अनुसार पिछले साल बजट पेश किए जाते समय सरकार ने अपने योजना मदों में 160 करोड़ रुपए अतिरिक्त होने की बात कही थी. लेकिन बाद में जब केंद्रीय महालेखाकार ने बजट की जांच की तो

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पाया कि असल में यह राशि केवल 40 करोड़ रुपए ही थी.

लेकिन दूसरी ओर राज्य सरकार ने आकस्मिक खर्च की मद में रखी जाने वाली राशि की सीमा अचानक ही 50 करोड़ से बढ़ाकर 350 करोड़ रुपए कर दी. इस मद में रखे गए धन को सरकार बिना पूर्व अनुमति के खर्च कर सकती है. इससे दुबे को बिना अंकुश अनाप-शनाप खर्च करने का हथियार मिल गया है.

अब राज्य सरकार के सामने आ खड़े हुए इस आर्थिक संकट ने दुबे को एक नाजुक हालत में खड़ा कर दिया है. असंतुष्ट विधायक कमलनाथ सिंह ठाकुर का कहना था, "दुबे को उनके सहयोगियों ने शायद यही सलाह दी है कि जल्दी से बजट अधिवेशन करवाकर उनका विकल्प खोजने की प्रक्रिया को नाकाम किया जा सकता है."

दुबे की गद्दी पर मंडराने वाले खतरे की वास्तविकता और गंभीरता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले ही महीने मिश्र ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात करके दुबे के विरुद्ध शिकायतों का पुलिंदा उन्हें थमाया था और आग्रह किया था कि राज्य सरकार के कार्यकलापों की जांच करवाई जानी चाहिए.

इन शिकायतों का एक नतीजा यह हुआ कि आलाकमान ने बिहार की स्थिति का आकलन करने के लिए सड़क परिवहन राज्यमंत्री राजेश पायलट और इंका महासचिव गुलाम नबी आज़ाद को बिहार भेजने का फैसला किया. इसी दौरान केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री योगेंद्र मकवाना समेत कुछ केंद्रीय नेताओं ने भी सार्वजनिक रूप से दुबे की इस बात के लिए आलोचना की कि उनकी सरकार भूमि सुधार कार्यक्रम लागू करने में असफल रही है. यह शिकायत आलाकमान तक भी पहुंचाई गई.

मगर इस सबके बावजूद दुबे का कुछ नहीं बिगड़ा. उलटे अब तक उनके कड़े आलोचक माने जाने वाले इंका कोषाध्यक्ष सीताराम केसरी ने उनके 1000 दिवस समारोह में भाग लेकर यह वातावरण पैदा करने की कोशिश की कि पार्टी आलाकमान का विश्वास अभी भी दुबे पर ही है. वैसे इस बारे में पार्टी के कुछ लोगों की राय यह है कि केसरी द्वारा की जाने वाली चरणवंदना का असली उद्देश्य अपने लिए फिर से राज्यसभा की नामज़दगी पाना है. इस मामले में सचाई कुछ भी हो पर एक सच तो दुबे साबित कर ही चुके हैं कि वे अपनी गद्दी बचाए रखने में कम माहिर नहीं हैं.

—फरजंद अहमद

मेघालय

सियासी झटके

इंका में असंतोष, विपक्ष बिखरा

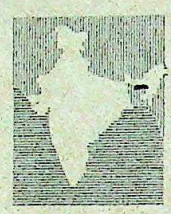

मेघालय की राजधानी शिलंग में भूकंप अक्सर आते रहते हैं. पर पिछले पखवाड़े शहर में महसूस किए गए झटके भूकंप के न होकर सियासी थे. राज्य के 68 वर्षीय मुख्यमंत्री कैप्टन विलियमसन ए. संगमा अमेरिका से फेफड़े का इलाज कराके लौटे ही थे कि उन पर

पुरना संगमा

विलियमसन संगमा

मुख्यमंत्री कैप्टन संगमा अमेरिका से अपने फेफड़े का इलाज कराके लौटे ही थे कि मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा

मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा.

सत्तारूढ़ इंका में असंतोष बेकाबू हो उठा और वह भी ऐसे वक्त जब 2 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं. संकेत मिले हैं कि आलाकमान मुख्यमंत्री को हटाकर उनकी जगह युवा केंद्रीय श्रम उपमंत्री पुरना ए. संगमा को लाने की सोच रहा है. पार्टी उम्मीदवारों की सूची में संगमा का नाम शामिल किया जाना मुख्यमंत्री के लिए पहले झटका था.

पर झटके यहीं नहीं रुके. पिछले पखवाड़े राज्य के मतदाताओं (आबादी करीब 14 लाख, अधिकतर आदिवासी) में तीन पेज एक पर्चा बांटा गया जिसमें भ्रष्ट और निकम्मी इंका सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की गई है. पर्चा किसी विपक्षी नेता ने नहीं बल्कि इंका सांसद जी.जी. स्वेल ने लिखा है. खासी जैंतिया आदिवासियों में स्वेल सरीखे प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा अपनी ही पार्टी के खिलाफ जेहाद की धमकी से राजनैतिक समीकरण बदलने लगे हैं.

पार्टी आलाकमान को भी इससे झटका ही लगा, क्योंकि सांसद जे.ई. ताहिझंग ने भी कैप्टन संगमा के कुर्सी पर बने रहने की सूरत में पार्टी छोड़ने की धमकी दी है. एक और मंत्री, कितदोर स्यिम तो इंका की गैर-जनजातियों के तुष्टिकरण की कथित नीति के विरोध में पहले ही विपक्षी खेमे में चले गए हैं.

राज्य के तीन लाख गैर-आदिवासी भी खार खाए बैठे हैं. 'विदेशियों' के खिलाफ खासी छात्रसंघ (केएसयू) की मुहिम का नजला मुख्यतः बड़ी तादाद में रहने वाले नेपाली समुदाय पर गिरा है. इससे इंका को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है क्योंकि गैर-आदिवासी ही वहां पार्टी का मुख्य आधार रहे हैं. इससे 60 सदस्यीय विधानसभा की करीब 15 सीटों पर पांसा पलट सकता है.

मगर संगमा कहते हैं, "हमारी जीत निश्चित है. विपक्ष की हालत बहुत पतली है. उसे यह भी मालूम नहीं कि वह क्या कर रहा है." शिलंग में सभी को मालूम है कि मुख्य विपक्षी दलों— हिल पीपुल्स यूनियन, हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और पब्लिक डिमांड्स इंप्लीमेंटेशन कन्वेंशन में बहुत कम राजनैतिक सामंजस्य है. नगालैंड के चुनावों की तरह यहां भी कोई राष्ट्रीय मुद्दा दांव पर नहीं है. मगर क्षेत्रीय पार्टियां राग अलापे जा रही हैं कि उनकी जातीय पहचान को बाहरी तत्वों से भारी खतरा है.

राजीव गांधी ने गारो हिल्स जिले के तूरा से चुनाव मुहिम शुरू की तो उन्होंने भी कहा कि केंद्र आदिवासी लोगों की जातीय पहचान को आघात पहुंचाए बिना उनके उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने विकास के लिए और धन देने की पेशकश करते हुए कहा कि मेघालय में प्रति व्यक्ति 4000 रुपए वार्षिक खर्च देश में सबसे अधिक है. पर पूर्व विधानसभाध्यक्ष और हिल पीपुल्स यूनियन के नेता राधून सिंह लिंगडोह पूछते हैं, "जब सरकार 95 रुपए के वाटर फिल्टर को 695 रुपए में खरीद रही है तो क्या खाक विकास हो रहा है?" घमासान मुकाबले की तैयारी हो चुकी है. मेघालय में जीतने के लिए इंका जीतोड़ कोशिश कर रही है ताकि त्रिपुरा में चुनाव में संभावित मार पर मरहम लग सके.

—रमेश मेनन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

21वीं सदी का कार्यक्रम

"सैम?"

"यस, बॉस?"

"मैं चिंतित हूं, सैम! हम 21वीं सदी की ओर नहीं जा पा रहे. मैं बतौर सरकार जो कुछ कर सकता था, सब कुछ किया. कई बार मंत्रिमंडल में फेरबदल कर चुका हूं. पर बात ही नहीं बनती!"

"बॉस, इसमें सरकार का क्या दोष! दरअसल आपकी पार्टी ने ही आपको नीचा दिखाया है. मंत्रिमंडल में फेरबदल छोड़कर आप पार्टी में नई जान फूकने की कोशिश कीजिए!"

"पर सैम मैं यह कैसे करूं?"

"बॉस, मेरे पास एक योजना है. इसे अमल में लाएं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा!"

"ठीक है सैम. बताओ क्या करें?"

"बॉस पहले 36 करोड़ का प्रबंध कर लीजिए. फिर मैं बताऊंगा कि क्या करें."

"क्या इधर-उधर की हांक रहे हो, सैम. 36 करोड़ क्या मामूली बात है? पर पैसे का मैं क्या करूंगा?"

"बॉस, देश भर में 500 दफ्तर खोल दीजिए. किराए पर, वेतन पर खर्च करना शुरू कर दीजिए!"

"पर सैम, ये दफ्तर क्या करेंगे?"

"बॉस, सही-सही लोग ढूंढिए और उन्हें बतौर सदस्य भर्ती कर लीजिए!"

"सही-सही लोग कौन हैं, सैम?"

"ऐसे लोग बॉस, जो वेतन लेना और खर्च करना मान लें!"

"ठीक है, सैम! यदि ऐसे लोग ढूंढ़ भी लिए जाएं तो वे करेंगे क्या?"

"वे ब्लॉकों और गांवों में नए दफ्तर खोलेंगे, बॉस!"

"पर सैम, ब्लॉकों और गांवों में खुलने वाले ये नए दफ्तर जिलों के पुराने दफ्तरों से भिन्न कैसे होंगे?"

"बॉस, जिला दफ्तर में तीन टेलीफोन होंगे, ब्लॉक दफ्तर में दो और गांव के दफ्तर में मात्र एक ही टेलीफ़ोन से काम चलेगा!"

"हूं! ठीक है! पर सैम मान लो हम देश भर में नए दफ्तर खोल भी लें तो वे करेंगे क्या?"

"बॉस, वे सदस्यता अभियान के तहत पार्टी में नए सदस्य भर्ती करेंगे!"

"मगर सैम इतने सारे सदस्यों का काम क्या होगा?"

"पार्टी की विचारधारा का प्रचार करना, बॉस!"

"और सैम, यह विचारधारा क्या होगी?"

"बॉस, आपको क्या याद नहीं— हमारी विचारधारा भारत को 21वीं सदी में ले जाने की है?"

"हां-हां, ठीक है! ठीक है! मगर सैम, हम भारत को 21वीं सदी में कैसे ले जाएंगे! कैसे पहुंचेंगे उसमें?"

"पार्टी कार्यक्रम पर अमल करके, बॉस!"

"लेकिन पार्टी कार्यक्रम क्या है सैम?"

"चंदा इकट्ठा करना, बॉस!"

"सिर्फ चंदा इकट्ठा करना? क्या हमारा कार्यक्रम समाजवादी नहीं माना गया था."

"हां, बॉस! यह समाजवादी ही है. हम अमीर और गरीब में कोई भेद नहीं करेंगे! दोनों से ही चंदा इकट्ठा करेंगे!"

"और धर्मनिरपेक्षता का क्या होगा?"

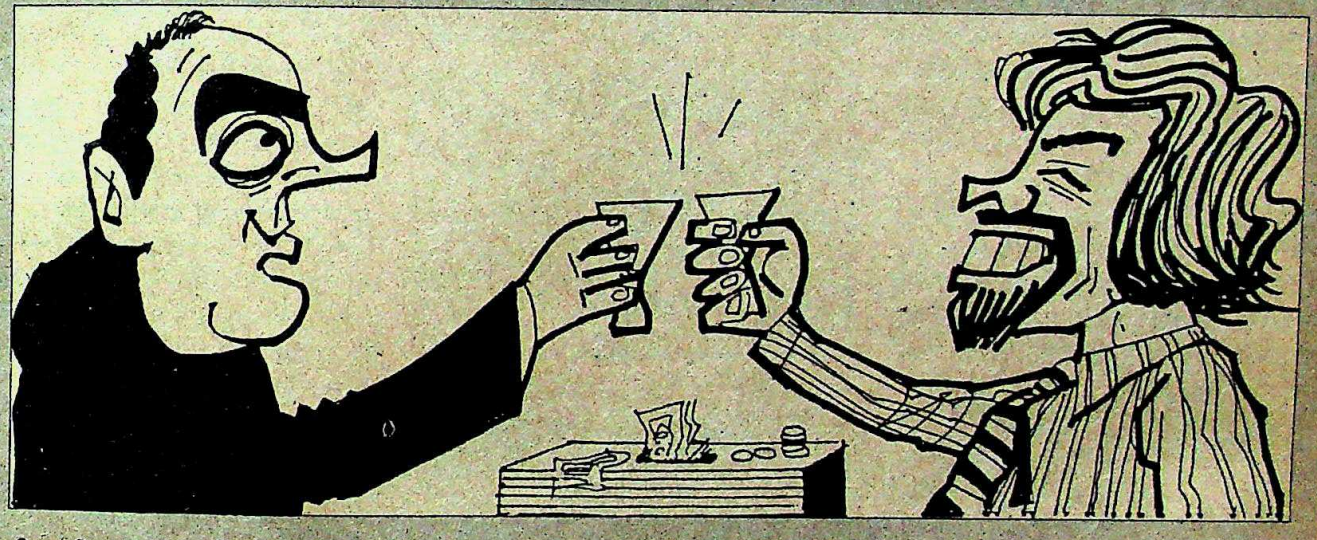

"इसमें भी हम कोई भेदभाव नहीं बरतेंगे, बॉस! हम हरेक से चंदा लेंगे— हिंदू हो, मुसलमान, सिख या ईसाई!"

"हूं. फिर तो बहुत-सा पैसा इकट्ठा हो जाएगा, सैम! फिर हम इतने सारे चंदे का क्या करेंगे?"

"और ज्यादा सदस्य भर्ती करेंगे, बॉस!"

"ये सभी सदस्य क्या करेंगे, सैम?"

"वे सब पार्टी कार्यक्रम पर अमल करेंगे और ज्यादा चंदा इकट्ठा करेंगे, बॉस!"

"और यही कार्यक्रम हमें 21वीं सदी में ले जाएगा क्या?"

"क्या ऐसा नहीं लगता, बॉस? हम पूर्ण रोजगार मुहैया करा देंगे! अमेरिका और रूस भी ऐसा नहीं कर पाए हैं."

"सैम, तुम वाकई प्रतिभाशाली हो..."

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ऑपरेशन पवन

जल्दबाजी का महंगा खामियाजा

भारतीय सेना पिटी तो पिटी, कई नए सबक भी उसे इस युद्ध में मिले

जाफना में दो महीने पहले खूनी लड़ाई लड़ने गई भारतीय सेना के लिए अब इसके नतीजे दर्ज करने का समय आ गया है. सैनिक अधिकारी नोट्स बना रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज—'युद्ध डायरी' लिखने के लिए अपने जूनियर कमांडरों से ब्यौरे हासिल कर रहे हैं. यह एक आधिकारिक वृत्तांत होगा और सेना भविष्य में इससे सीख ले सकेगी. 'इंडिया टुडे' ने 'अपनी डायरी' बनाने के लिए विशेष संवाददाता ***शेखर गुप्ता*** *को जनरलों से लेकर जाफना के जंगलों में जूझ रहे सैनिकों तक से मुलाकात करने का जिम्मा सौंपा था. उनकी रिपोर्ट:*

घने जंगलों से आच्छादित मिजोरम की पहाड़ियों पर एक जगह है वैरंगटे. वहां भारतीय सेना ने अपना 'काउंटर इंसरजेंसी ऐंड जंगल वारफेअर स्कूल' बना रखा है. यह एक प्रशिक्षण केंद्र है जहां सैनिकों को गुरिल्ला छापामारों और बागियों से निबटने की तालीम दी जाती है. इस केंद्र का आदर्श वाक्य है—'छापामारों से छापामारों की शैली में ही निबटो'. मिजोरम और नगालैंड में दो दशक पहले बागी सिर उठाने लगे थे. तभी इस केंद्र की स्थापना की गई थी.

लेकिन प्रशिक्षण के बावजूद पिछले अक्तूबर में तमिल मुक्ति चीतों (एलटीटीई) से हथियार डलवाने के लिए की गई सैनिक कार्रवाई में भारतीय सेना से कई गंभीर गलतियां हुईं और उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा. 350 से ज्यादा सैनिक मारे गए और 1100 घायल हुए. यह संख्या युद्धरत कुल सैनिकों की सात प्रतिशत और पहले लड़े गए बड़े युद्धों के हताहतों से करीब दुगुनी है.

छापामार युद्ध के अनुभव के बावजूद भारतीय सेना को इस युद्ध में जान-माल की भारी क्षति उठानी पड़ी

इस कार्रवाई पर नजर दौड़ाने से साफ हो जाता है कि गलतियां कहां-कहां हुईं. एक अफसर का कहना है, "दुश्मनों की ताकत और हमारे लक्ष्यों के बारे में राजनैतिक नेताओं के अनुमान यदि सही निकलते तो आज कहानी कुछ और होती." राजधानी में बैठे नीति निर्माताओं की जल्दबाजी और अत्यधिक आत्मविश्वास का ही नतीजा था कि सेना की चार ब्रिगेडों को जाफना में झोंककर परेशानी में डाल दिया गया. राजनैतिक नेता जल्दबाजी में थे तो सेना के अधिकारियों ने भी उसे चुपचाप स्वीकार कर लिया. फलस्वरूप 11 अक्तूबर को सेना की जिन इकाइयों को कार्रवाई में भेजा गया

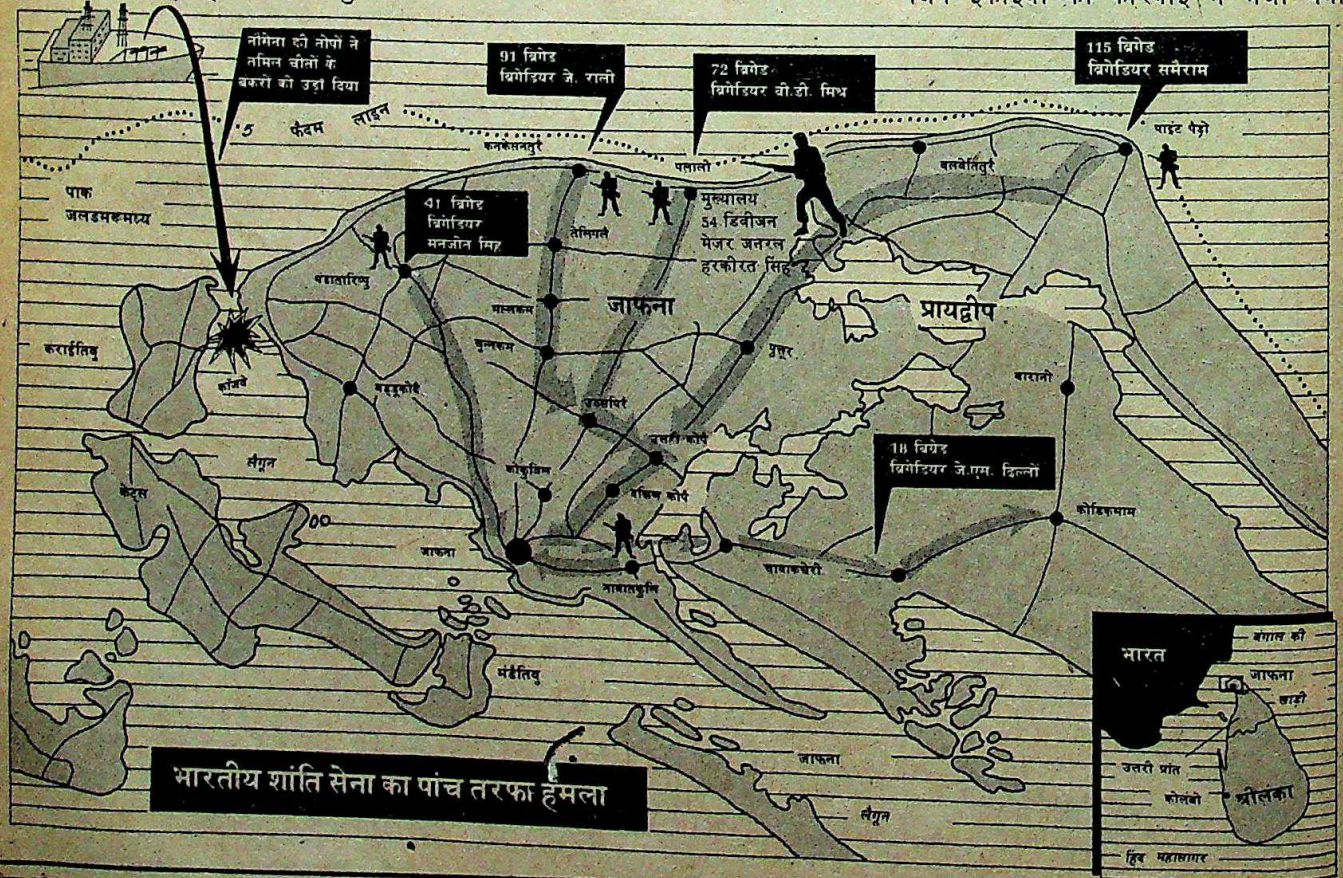

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नमी फोटो शेखर गुप्ता

उनमें सैनिक कम थे, उनके पास शस्त्रों की कमी थी, उन्हें स्थिति का ब्यौरा ठीक-ठीक नहीं दिया गया था:

► सेना की कई इकाइयों को तो 11 अक्तूबर को श्रीलंका भेजने के कुछ घंटों बाद ही जंग में झोंक दिया गया. 4/5 गोरखा और 13 सिख लाइट इन्फैंट्री बटालियनें तो जाफना भेजे जाने के कुछ ही घंटों पहले उतरी थीं. इन बटालियनों के हताहतों की संख्या 110 से भी ज्यादा है. 13 सिख लाइट इन्फैंट्री को अगस्त में जाफना भेजने के लिए विमान से बंगलूर लाया गया लेकिन 7 अक्तूबर को उन्हें ग्वालियर भेज दिया गया. दूसरे ही दिन फिर उनसे जाफना जाने के लिए तैयार होने को कहा गया. आखिरकार यह बटालियन 11 अक्तूबर को ही जाफना पहुंच पाई. और विदेशी जमीन पर उतरने के कुछ ही घंटों के भीतर उन्हें मैदाने-जंग में उतार दिया गया. इसी तरह 41 ब्रिगेड को 17 अक्तूबर को विमान से ले जाकर सीधे समुद्र के किनारे से होकर जाफना किले तक पहुंचने वाले रास्ते पर लगा दिया गया. (रेखाचित्र देखें) इस ब्रिगेड के 272 जवान हताहत हुए.

► लड़ाई शुरू हुई तो भारतीय शांति सेना के पास सिर्फ छह आर्टिलरी गन तथा तीन टी-72 टैंक थे. एक अधिकारी ने कहा, "आमतौर पर किसी बटालियन को हमले में सहायता देने के लिए करीब 200 आर्टिलरी गन होती हैं जबकि हमारे पास 20 से ज्यादा बटालियनों के लिए सिर्फ छह आर्टिलरी गन ही थीं." हवाई और नौसैनिक हमलों के लिए विशेष रूप से बनाई गई 54 इन्फैंट्री डिवीजन के सामरिक मुख्यालय को पलाली ले जाया गया लेकिन बड़े हथियार गैरजरूरी मानकर छोड़ दिए गए और लड़ाई शुरू हुई तो

11 अक्तूबर को सेना की जिन इकाइयों को लड़ाई में लगाया गया उनके पास जवान, हथियार कम थे और वे थकी हुई थीं

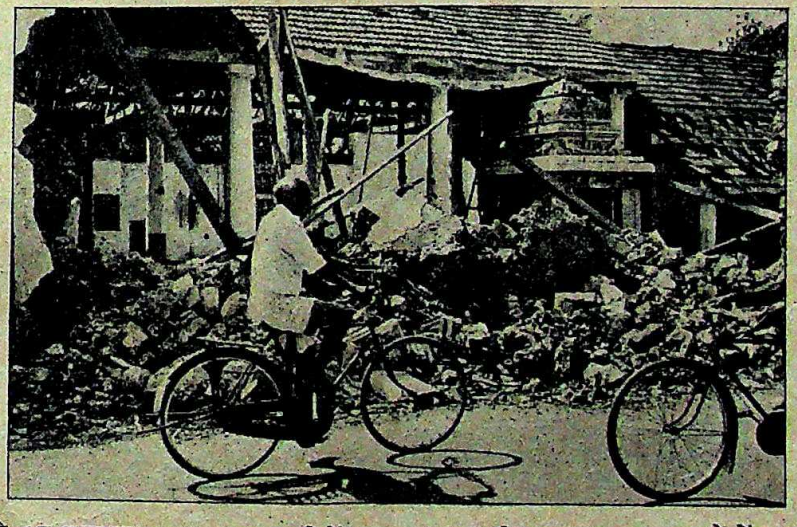

लड़ाई में बरबाद हुए मंदिर के खंडहर: युद्ध से आक्रांत शहर

जाफना में शांति सेना का पहरा: महंगी जीत

हथियार सप्लाई की रफ्तार बहुत ही धीमी रही. आईएल-76 जेट सिर्फ एक टी-72 टैंक या दो बीएमपी बख्तरबंद लड़ाकू गाड़ियां लेकर ही पहुंचता रहा क्योंकि कांकेसंतुरई बंदरगाह के घाट एक साथ कई भारी हथियार उतारे जाने के काबिल नहीं थे.

► कई बार गोला-बारूद की भी कमी पड़ी. मुक्ति चीते घात लगाकर हमला कर रहे थे इसलिए सड़क से गोला-बारूद भेजना काफी मुश्किल हो गया था. गोला-बारूद पहुंचाने में हेलिकॉप्टर लगाए गए. नवातकुली के नजदीक एक बार महार बटालियन यह देखकर दंग रह गई कि उनके लिए गोला-बारूद उनके नियंत्रण क्षेत्र से बाहर गिराया जा रहा है. अपने ही हथियार हासिल करने के लिए उन्हें मुक्ति चीतों का घेरा तोड़ना पड़ा.

► टैंकों तथा हेलिकॉप्टर गनशिपों से जो कार्रवाई आमतौर पर वैसे ही की जानी चाहिए थी उसके लिए भी नई दिल्ली से राजनैतिक मंजूरी का 16 घंटों तक इंतजार किया गया. दिल्ली की हरी झंडी मिलते ही जब हेलिकॉप्टर गनशिप उतारे गए तो उन्होंने अपनी उपयोगिता तुरंत साबित कर दी. चावाकचेरी पर हेलिकॉप्टर गनशिपों से सिर्फ 32 रॉकेट दागने के बाद ही मद्रास रेजीमेंट की दो बटालियनों ने मात्र तीन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जवानों की कीमत पर मुक्ति चीतों का एक मजबूत गढ़ फतह कर लिया. एक सैनिक अफसर कहते हैं, "हेलिकॉप्टर गनशिपों का अगर इस्तेमाल न किया जाता तो मुक्ति चीतों के उस मजबूत दुर्ग को भेदने में हमारे कम-से-कम 100 सैनिकों को प्राणों की आहुति देनी पड़ जाती."

कई बार तो मुक्ति चीतों की गोलियों से अधिकारियों के हताहत होने के कारण भी सैनिक टुकड़ियां अशक्त हो गईं. किसी टुकड़ी का अधिकारी मारा या घायल हो जाता तो उसके नीचे के अधिकारी तथा सैनिक पहल नहीं कर पाते थे. ऐसी ही स्थिति में फंसी 4/5 गोरखा बटालियन जो अपनी बहादुरी के लिए मशहूर है, 1965 के जम्मू के राजौरी क्षेत्र में और 1971 की लड़ाई में इसने और बेहतर प्रदर्शन किया. दोनों लड़ाइयों में बटालियन के सिर्फ 58 जवान शहीद हुए थे लेकिन जाफना में इस बटालियन को अपने 70 जवानों के प्राणों से हाथ धोने पड़े.

इस बटालियन को 72 ब्रिगेड के एक हिस्से के रूप में जाफना की तरफ बढ़ते हुए जाफना विश्वविद्यालय परिसर में हेलिकॉप्टर से उतारी गई सैनिक टुकड़ियों से जा मिलना था. गोरखा बटालियन के सैनिक परिसर से पैराकमांडो सैनिकों तथा टैंकों के साथ आगे बढ़े (बाक्स देखें). टैंक तो सुरक्षित रास्तों से आगे बढ़ते रहे पर उरूम्पराई में मुख्य सड़क के चौराहे पर स्थित चार मंदिरों से पीछे चल रहे गोरखा सैनिकों पर एकाएक भारी गोलाबारी होने लगी. बटालियन के एक बहादुर अफसर, मणिपुर के मेजर एन.जे.डी. सिंह के सिर में गोली लगी और वहीं उनका प्राणांत हो गया. एक सुरंग फटने से दूसरे कंपनी कमांडर मेजर अनिल दीपक गार्डनर के पैरों का पूरा मांस ही बाहर निकल आया. पूरी इकाई में एकमात्र तमिलभाषी कंपनी कमांडर मेजर ए.ए. वर्गीज एक मकान में औरतों, बच्चों की चीख-पुकार सुन उन्हें सांत्वना देने

कमांडो कार्रवाई

खूनी रात की दुखद स्मृति

भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर चेतक के कॉकपिट से नीचे की एक झलक ही उन सैकड़ों अफवाहों से ज्यादा कुछ कह जाती है कि 11 अक्तूबर की शाम को तमिल मुक्ति चीतों के नेताओं को पकड़ने के लिए कमांडो कार्रवाई के दौरान क्या घटा होगा. जल्दी सफलता पाने के लिए की गई इस कार्रवाई का परिणाम अंततः एक खूनी हादसे में बदल गया था.

शहर पूरी तरह खपरैल की छतों और ताड़ के वृक्षों से आच्छादित लाल और हरा दिखता है. खाली जगह के रूप में साफ-साफ सिर्फ दो ही स्थान दिखते हैं. एक फुटबाल का मैदान और दूसरा उससे छोटा एक और मैदान. ऐसे हालात में किसी भी सैनिक अधिकारी से गलती नहीं होनी चाहिए थी.

तमिल मुक्ति चीतों के मुख्यालय का सफाया करने के लिए 'अचानक सैनिक कार्रवाई' का निर्णय लिया गया. इस कार्रवाई के लिए एमआई-8 हेलीकॉप्टर से सैनिकों को उतारा जाना था. पैराशूट का प्रयोग न करने का भी फैसला लिया गया था. योजना के अनुसार पहले विशेष '10 पैरा-कमांडो बटालियन' की एक कंपनी (करीब 70 सैनिक) को उतारा जाना था, जो फुटबाल के मैदान को अपने कब्जे में ले लेंगे. उसके बाद कई हेलीकॉप्टरों से '13 सिख लाइट इन्फैंट्री' के जवानों को पैरा-कमांडो सैनिकों की सहायता के लिए उतारा जाना था. सिख लाइट इन्फैंट्री के जवानों को कुछ घंटे पहले ही ग्वालियर से विमान से ले जाया गया.

लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टरों से सैनिकों को गिराना प्रारंभ हुआ कि इन पर भीषण गोलाबारी शुरू हो गई. उच्च क्षमता वाली (.5 इंच तक की) मशीनगन से चलाई गई गोलियों से हेलीकॉप्टर खुद ही खतरे में पड़ गए. जैसे-तैसे कमांडो सैनिकों को उतारा गया. सैनिकों ने अंधाधुंध गोलाबारी के बीच फुटबाल मैदान के नजदीक के मकानों में मुक्ति चीतों के नेताओं को खोजना शुरू किया जो वहां से पहले ही भाग चुके थे. इस तरह इसमें छह सैनिक मारे गए तथा नौ सैनिक घायल हो गए.

लेकिन इससे भी बदतर हालत तो बाद में हुई, जो जाफना युद्ध की सबसे त्रासद अनकही कहानी है. अंधेरी रात तथा मशीनगनों की अंधाधुंध गोलाबारी के बीच 'सिख लाइट इन्फैंट्री' के 30 सैनिकों को हेलीकॉप्टरों ने दूसरे छोटे मैदान में उतार दिया. यह मैदान फुटबाल मैदान से तो कुछ गज दूरी पर ही था, लेकिन इनके बीच मकानों की कई पंक्तियां हैं. इन सभी गलियों में मुक्ति चीतों ने बंकर तथा सुरंगें बिछाई हुई थीं (रेखाचित्र देखें).

बहादुर मजहबी सिख सैनिकों ने मुक्ति चीतों के बंकरों के बीच उतरकर समझा कि जरूर कुछ गड़बड़ी हुई है. उन पर गोलियों की बौछार शुरू हो गई. तीन हेलीकॉप्टरों में भी गोली लगी. पायलटों ने हेलीकॉप्टरों को किसी तरह पलाली पहुंचाया और यह दुखद

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गए तो वहां एक बूढ़ी औरत ने उनकी पीठ में गोली मार दी.

एक गोली आई और बटालियन के कमांडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल आई.बी.एस. बावा के दिल के ठीक नीचे जा घुसी. उन्हें घायलों के साथ एक सूखे कुएं में ले जाया गया. यही छिपने का एकमात्र स्थान था. वहां एक डॉक्टर उन्हें बचाने के लिए जी-जान एक करता रहा. इसके बाद मुक्ति चीते उस कुंए पर गोलियां बरसाने लगे. इस गोलाबारी से डॉक्टर को मामूली चोट आई और वह चमत्कारी रूप से बच गया पर लेफ्टिनेंट कर्नल बावा जीवन-मृत्यु के बीच झूलते रहे क्योंकि मुक्ति चीतों की धुंआधार फायरिंग के कारण हेलिकॉप्टर उन्हें कुंए से उठा नहीं सके. जब बचाव अभियान पर निकला टैंकों का जत्था वहां पहुंचा तो कर्नल बावा की मृत्यु हो चुकी थी. गोली लगने के छह घंटे बाद शाम 4.30 बजे उनकी मौत हुई.

मुक्ति चीतों ने नियोजित तरीके से अफसरों को ही अपना निशाना बनाया. बख्तरबंद गाड़ी पर चल रहे कर्नल डी.एस. सराओं और उनके 9 साथी एक बारूदी सुरंग फटने से मारे गए. छापामारों ने 5 राजपूताना के मेजर ए.के. चतुर्वेदी को भी गोली मार दी और लेफ्टिनेंट आर.एस. नागर को मार डाला. तोपखाना रेजिमेंट के डॉक्टर मेजर आर.एस. कनवा को भी अपनी गोलियों का निशाना बनाया.

वरिष्ठ अधिकारियों के मारे जाने से सैनिकों की आगे बढ़ने की गति पर भी बुरा असर पड़ा. मेजर चतुर्वेदी की लाश हासिल करने की कोशिश में ही एक जवान मारा गया. रक्षा मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्र भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि पाकिस्तान के साथ हुई लड़ाइयों के मुकाबले श्रीलंका कार्रवाई में शहीद हुए अफसरों की तादाद बहुत ज्यादा रही है. छापामार अफसरों पर छांटकर निशाना लगाने की हालत में थे. इस

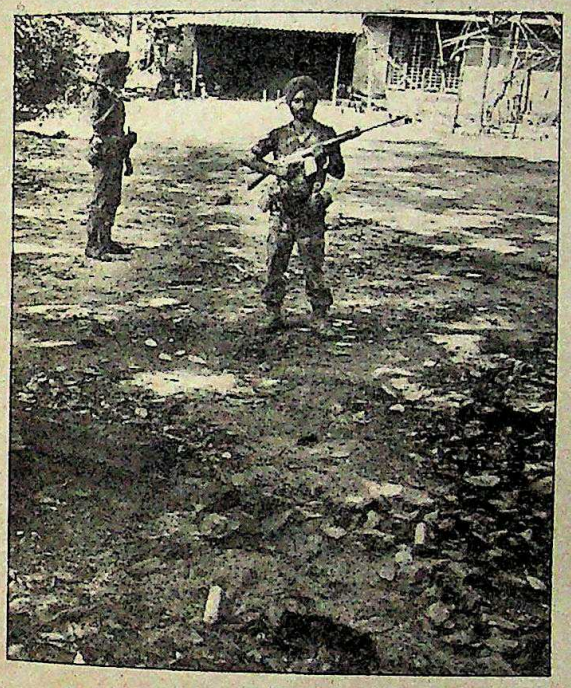

युद्धभूमि में बिखरे सिख रेजिमेंट की पोशाक के चीथड़े

समाचार दिया कि पूरी प्लाटून तथा बाद में भेजी गई सैनिक टुकड़ी दोनों का सफाया कर दिए जाने की आशंका है.

लेकिन इस सैनिक टुकड़ी तथा उसके नौजवान कमांडर मेजर वीरेंद्र सिंह का साथ भाग्य ने भी नहीं दिया और वे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते थे. मेजर वीरेंद्र सिंह भरतपुर के प्रसिद्ध राजघराने से हैं तथा विदेश राज्यमंत्री नटवर सिंह के रिश्तेदार हैं. लगता है कि इस टुकड़ी का रेडियोमैन ही सबसे पहले मारे जाने वालों में था, जिससे पलाली से उनका संबंध टूट गया.

उधर कमांडो उनसे आगे बढ़ने तथा उनसे आ मिलने की कोशिश करने को कह रहे थे, जबकि मेजर वीरेंद्र सिंह बाकी कंपनी के आ जाने का इंतजार करते रहे. वे नहीं जानते थे कि बाकी कंपनी अब नहीं पहुंच रही है. और जब तक उन्हें इसका आभास हुआ तब तक वे इतनी बुरी तरह घिर चुके थे कि बाहर निकलने की बाबत सोचना भी उनके लिए मुश्किल हो गया था. मुक्ति चीतों ने सारी रात गोलाबारी जारी रखी. 'सिख लाइट इन्फैंट्री' इसका जवाब देती रही और मूल्यवान गोला-बारूद बरबाद करती रही. आखिर 12 अक्तूबर को 11.30 बजे दिन में जब अंतिम गोली खत्म हो गई तो भारतीय टुकड़ी ने संगीनों से हमला शुरू किया. इस तरह भारतीय टुकड़ी में सिर्फ सिपाही गोरा सिंह बच गए. उन्हें मुक्ति चीतों ने बंदी बना लिया और बाद में उनकी रिहाई हुई. उनके बयानों से ही भारतीय सेना के इतिहास की इस सबसे दुखद लड़ाई की कहानी उजागर हुई.

भारतीय सैनिकों के नंगे शव नागराज विहार मंदिर के पास लोगों को देखने के लिए डाल दिए गए थे. उसके बाद लाशों के ढेर पर तेल छिड़ककर उन्हें जला दिया गया. इस हादसे के निशान आज भी पास की एक इमारत—मुक्ति चीतों का पूर्व अड्डा— में दिखते हैं भारतीय सैनिकों के क्रास-बेल्ट, जूते, बोतलें, .50 इंच मशीनगन की गोलियों के खाली कारतूस वहां आस-पास बिखरे पड़े हैं.

जब सिख लाइट इन्फैंट्री की टुकड़ी अंतिम लड़ाई लड़ रही थी, तब कमांडो की सहायता के लिए एक बड़ा बचाव अभियान भी जारी था. पैराकमांडो बटालियन के कमांडर लेफ्टीनेंट कर्नल दलबीर सिंह ने खुद ही तीन टी-72 टैंकों के साथ इस कार्रवाई को प्रारंभ किया. उस समय श्रीलंका में भारतीय सेना के पास कुल इतने ही टैंक थे. सड़कें बंकरों से पटी हुई थीं, इसलिए टैंक ट्रुप के कमांडर मेजर अनिल कौल ने एक नया रास्ता अपनाने का निर्णय लिया. उन्होंने पलाली-जाफना रेल लाइन के रास्ते से टैंकों को ले जाने का फैसला किया. रेल लाइन उस कैंपस के एकदम पास से गुजरती थी. कौल को खुद आंख और दाहिने हाथ में गोली लगी. वे एक क्षण के लिए रेल लाइन का रास्ता देखने के लिए बाहर निकले थे. लेकिन उनके सैनिक कैंपस की तरफ आगे बढ़ने में अभी भी सक्षम थे और जब टैंक मुक्ति चीतों की घेराबंदी को तोड़कर पैराकमांडो सैनिकों के साथ पलाली लौटने वाले थे तभी 415 गोरखा पैदल टुकड़ी और 13 सिख लाइट इन्फैंट्री की मुख्य पैदल टुकड़ी भी उनसे आ जुड़ी.

अगर पैराकमांडो सैनिक इस हादसे में अपने को बचा सके, तो उसका श्रेय उनके बेहतर प्रशिक्षण को ही दिया जाना चाहिए. वे गोला-बारूद बचाए रख सके, कई मकानों को अपने कब्जे में ले सके तथा यहां तक कि अपने मृतकों, घायलों तथा उनके हथियारों को भी ले आए.

यह खूनी रात अब भारतीय सेना के इतिहास तथा युद्ध डायरियों के पन्नों का अविभाज्य अंग बन गई है. यह उन जांबाज सैनिकों की दुखद स्मृति का भी हिस्सा बन गई है जो उस कार्रवाई में शामिल थे. खासकर 13 सिख लाइट इन्फैंट्री के बच रहे सैनिक अब हर साल 12 अक्तूबर को जाफना विश्वविद्यालय के मैदानों में मारे गए अपने 30 साथियों की याद में विशेष अरदास तथा अखंड पाठ का आयोजन करेंगे.

—शेखर गुप्ता, कोलंबो में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नुकसान से सेना को एक नया सबक मिला है कि इस तरह की कार्रवाइयों में अफसरों को भी दूसरे जवानों जैसी वर्दी में रखा जाए और उन्हें दस्ते में सबसे आगे न रखा जाए.

जाफना के तुजर्बे से कई और अहम सवाल भी उठे हैं. अधिकारी मानते हैं कि कार्रवाई के दौरान मूल रणनीति का पालन नहीं किया गया. इस खास रणनीति के तहत छापामारों के इलाके में बढ़ने वाले दस्ते 10-15 की तादाद में आगे-पीछे चलते हैं. जब एक दस्ता आगे बढ़ता है तब पीछे वाला दस्ता फायरिंग करके उसे कवर देता रहता है. इस कवर की सीमा तक पहुंचने के बाद अगला दस्ता रुक जाता है और फायरिंग शुरू करके पिछले दस्ते को आगे बढ़ने के लिए कवर दे देता है. जाफना में हर जगह इस रणनीति का इस्तेमाल नहीं किया गया.

इस कार्रवाई का एक और सबक था कि आवासीय और सुरंगों से लैस इलाकों में बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल बेअसर रहता है. मुक्ति चीतों ने इन इलाकों में हथगोला फेंकने वाले चीन निर्मित राकेट लांचरों (आरपीजी) का भी इस्तेमाल किया. कम दूरी से इनकी मारक क्षमता बहुत घातक रही. डिवीजन कमांडर मेजर जनरल हरकीरत सिंह बताते हैं, "उन्होंने टैंकों पर पेट्रोल से भरे और जलते हुए कनस्तरों से भी हमले किए."

इसके अलावा सेना को पहली बार यह समझ आया कि एकदम आमने-सामने की लड़ाई में उसकी 7.62 मिमी वाली राइफलें 'कालाश्निकोव एके-47' के मुकाबले एकदम नकारा हैं. ये न सिर्फ वजनी हैं बल्कि एक बार में केवल एक गोली छोड़ती हैं जबकि छापामारों की कालाश्निकोव से गोलियों की जैसे बाढ़ ही लग जाती है. इस अनुभव के बाद अब शायद 7.62 मिमी के स्थान पर 5.56 मिमी वाली हल्की राइफलों का प्रयोग शुरू किया जाए.

भविष्य में भारतीय सेना को मुक्ति चीतों द्वारा सुरंगों के इस्तेमाल की महारत से भी बहुत कुछ सीखना होगा. भारतीय पक्ष में शहीद हुए 60 प्रतिशत से भी अधिक सैनिक इन्हीं सुरंगों के शिकार हुए. ये सुरंगें धातु के खोल के बजाय प्लास्टिक के सामान्य डिब्बों में बारूद भरकर बनाई गई थीं. एक जनरल के शब्दों में, "सुरंगें बनाने में उन्होंने किसी भी गैर-धातु पदार्थ का इस्तेमाल करने में संकोच नहीं किया. यहां तक कि नारियल के खोखले तने को भी उन्होंने सुरंग के खोल की तरह इस्तेमाल किया." इन सुरंगों के तारों को बहुत सफाई से किसी घर तक ले जाया गया. कुछ मामलों में यह दूरी एक किलोमीटर तक पाई गई. इन सुरंगों के नक्शे मुक्ति चीतों के पास रहते थे और जब भी कोई अच्छा 'शिकार' किसी सुरंग के ऊपर से गुजरता वे तारों को जोड़कर उसे उड़ा देते. एक अफसर का कहना था, "इनमें से कुछ सुरंगों में तो 200 किलोग्राम तक विस्फोटक बारूद थी जिसकी प्रभावी मारक क्षमता एक किलोटन तक हो सकती है." हिरोशिमा पर फेंके गए एटम बम की शक्ति 20 किलोटन थी.

तमिल चीतों ने घात लगाने के लिए बैठने की सुरक्षित जगहें बनाकर और मील के पत्थरों पर कालिख पोतकर सेना को त्रस्त किया

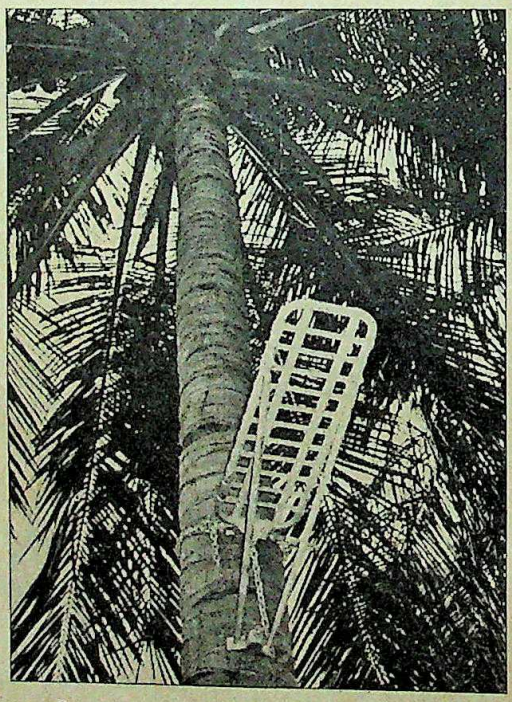

साफ है कि इन बारूदी सुरंगों ने भारी कहर ढाया. एक विस्फोट में 45 टन वजन वाले एक टी-72 किस्म के टैंक के टुकड़े-टुकड़े हो गए. इसी तरह कर्नल सराओं की 20 टन वजनी बख्तरबंद गाड़ी (बीएमपी) भी विस्फोटक में 30 फुट ऊंची उछल गई और 250-250 किलो वजन के उसके दरवाजे टूटकर 100 गज दूर जा गिरे.

इतनी भारी कीमत चुकाने के बाद सेना भी समझदार हो चुकी है. एक बड़े सैनिक अधिकारी का कहना था, "जाफना से जितने सबक भारतीय सेना को मिले हैं उतने शायद किसी और को नहीं मिले."

इसके अलावा भारतीय सेना ने इस कार्रवाई में कुछ नए परीक्षण भी किए हैं. इनमें इलेक्ट्रॉनिक युद्ध से लेकर हेलिकॉप्टरों से हमले और टी-72 किस्म के टैंकों से लेकर मारुति जीप तक कई उपकरणों पर किए जाने वाले परीक्षण भी शामिल हैं.

इस कार्रवाई के दौरान कई चीजें पहली बार हुईं. पहली बार थल, जल और वायुसेना ने साझा कार्रवाई में हिस्सा लिया; किसी असली लड़ाई में पहली बार हेलिकॉप्टर गनशिप प्रयोग किए गए; और जाफना व करईतीवू टापू को जोड़ने वाले इलाके में छाताधारी कमांडो दस्तों पर मुक्ति चीतों के हमलों को नाकाम करने के लिए एक बड़े युद्धपोत से गोले दागकर उनके बंकर ध्वस्त किए गए. बख्तरबंद गाड़ियों को समुद्रतट पर उतारने के लिए भी पहली बार लैंडिंगशिप ट्रांसपोर्ट प्रणाली का प्रयोग किया गया.

इस कार्रवाई के दौरान वायुसेना और इंडियन एअर लाइंस ने एक पखवाड़े में 4100 उड़ानें भरकर मद्रास और जाफना के बीच हवाई पुल-सा बांध दिया. परिणाम यह हुआ कि जाफना और वावुनिया हवाई अड्डे के रनवे जगह-जगह पर धंस गए.

कार्रवाई के अपेक्षाकृत शांत हो जाने पर दूसरी तरह के कई प्रयोग भी हाथ में ले लिए गए हैं. मुक्ति चीतों के संचार संबंधों पर नजर रखने के लिए नई इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों का इस्तेमाल किया जा रहा है और छापामारों के ठिकाने ढूंढ़ने के लिए जगुआर विमानों को फोटोग्राफी वाली टोही उड़ानों पर भेजा जा रहा है. लेकिन सबसे बड़ा सबक यह मिला है कि किसी जुझारू और हथियारबंद दुश्मन को कमजोर मानकर न चला जाए.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जापान का ओसाका शहर अब दिल्ली से सिर्फ १८ किलोमीटर दूर

दिल्ली से १८ किलोमीटर दूरी पर आप पाएंगे ओसाका: जहां कि आपको नज़र आएगी पंखे तैयार करने वाली उतनी ही उत्कृष्ट और उतनी ही आधुनिक इकाई, जैसे कोई जापानी इकाई।

जहां आप देखेंगे भारत की सबसे पहली सीधी खड़ी इन्टिग्रेटेड कन्वेयर वाली असेम्बली लाइनें, क्रोम फ़्लैशिंग जैसी अति आधुनिक तकनीक, क्वालिटी नियंत्रण के लिए कंप्यूटरचालित प्रणालियां और यहीं आप पाएंगे वो अनुसंधान एवं विकास विभाग, जिसने तैयार किया है एक अनोखा उत्पादन: टेलिस्कोपिक ऑसिलेटिंग टेबल फ़ैन... एक स्विच के दबाते ही जो बन जाए मिनी–पैडस्टल फ़ैन।

ये इकाई है पोलर की। एक ऐसी कंपनी जिसने वादे नहीं किए बल्कि हमेशा अपनी बेहतरीन कामगिरी के सुबूत पेश किए: १ करोड़ २५ लाख संतुष्ट ग्राहक। ३,००० कुशल डीलरों की विस्तृत सेवाएं। और कारखानों में प्रशिक्षित कर्मचारियों से लैस देश-भर में फैलें २४ सेवा केंद्र।

इसलिए अबके जो आप चाहें आने वाले कल की शानदार खूबियों वाला पंखा, तो याद रखिए–अगले मोड़ पर ही २१वीं सदी का करिश्मा आपके इंतज़ार में है ... पोलर पंखों के डीलरों के पास।

पोलर

वह उत्कृष्ट कंपनी
जो बुनियाद है उत्कृष्ट पंखों की

LINTAS:CAL:PCF/32/21/201-Hi

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मद्रास

पुराने शहर का नया रंगरूप

टूटती परंपराएं, सिमटती रूढ़ियां, बदलते जीवन-मूल्य व जीवन-शैली

रूढ़ियों का गढ़ मद्रास आधुनिक हो रहा है? जानकारों को शायद भरोसा न हो पर पिछले कुछ वर्षों में शहर ने तेजी से परंपराएं तोड़ी है. बदलते परिवेश पर वरिष्ठ संवाद-दाता ***एस.एच. वेंकटरमनी*** *की एक नजर:*

कृष्णस्वामी आयंगर (60) पारंपरिक तरीके से धोती पहनने वाले व्यक्ति हैं. उनके माथे पर लगा चंदन उन दिनों की याद दिलाता है जो कभी मद्रास की जीवन-शैली व संस्कृति का प्रतीक हुआ करता था. उनकी शादी भी पारंपरिक ढंग से हुई थी और उनकी पत्नी नौ गज की साड़ी पहनने वाली महिला हैं. आयंगर दिन निकलते ही मंदिर जाते और सुबह नौ बजे ही दिन का भोजन कर लेते. सफेद सूती कमीज और मुड़े पांयचों वाली पैंट पहनकर दफ्तर जाते हुए उनके हाथ में एक टिफिन होता था जिसमें इडलियां व चटनी होती थी. कभी-कभार ही वे अपने परिवार को एक उडुपी होटल में इडली-वडा खिलाने ले जाते थे. और सिनेमा तो उनका परिवार साल में एक बार जा सकता था. शराब देखकर वे थरथरा जाते. सिगरेट उनके लिए सबसे बड़ा ऐब था.

करीब एक दशक पहले एक औसत मद्रासी का जीवन कृष्णस्वामी आयंगर जैसा ही था. पर अब आयंगर का 30 वर्षीय बेटा के. संपत, जो एक निजी कंपनी में अधिकारी है, जींस और फैशनेबल कमीजें पहनता है. वह अपनी पत्नी निर्मला से कॉलेज में मिला था और उनकी शादी अदालत में हुई. निर्मला ने बाल कटा रखे हैं और काम पर वह आम तौर पर शिफॉन की साड़ियां पहनना पसंद करती

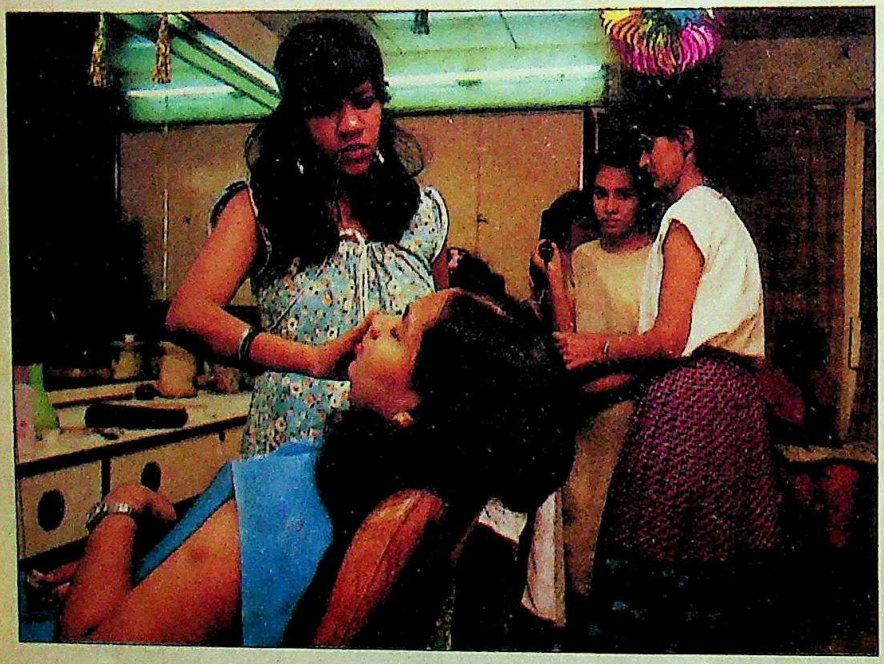

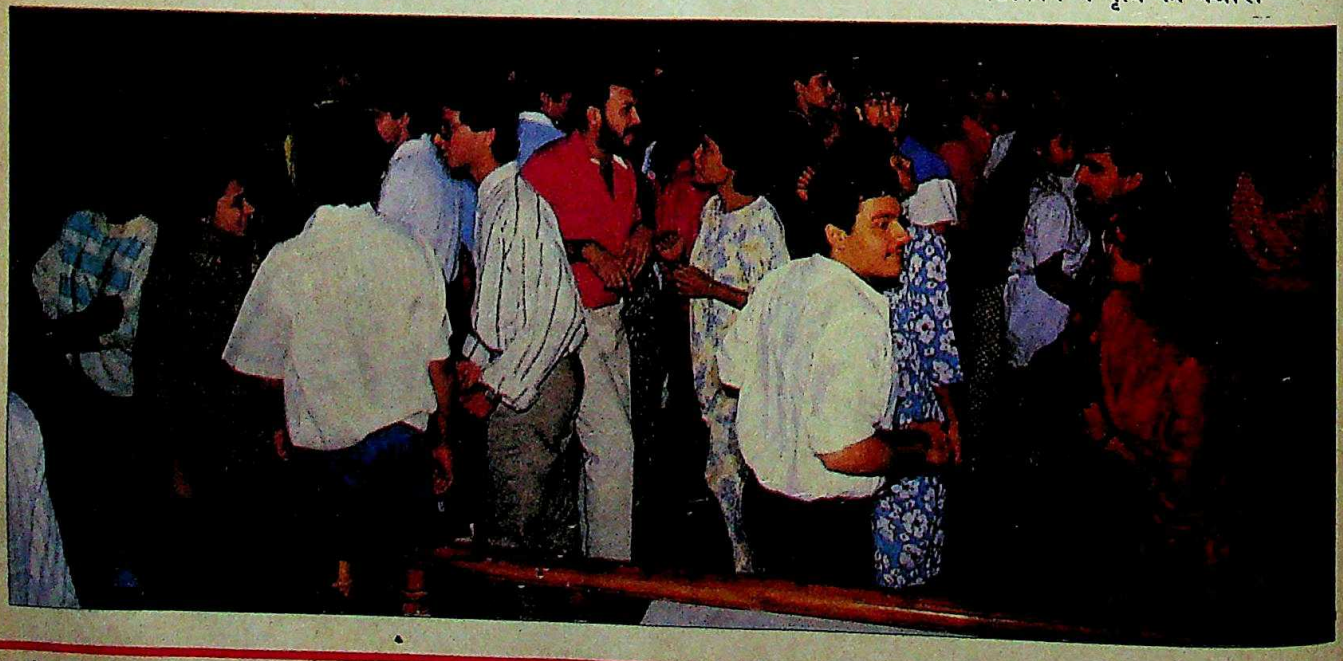

एक ब्यूटी पार्लर (बाएं); और नए खुले डिस्कोथे में नृत्य का नजारा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हैं, जबकि पार्टियों में विदेशी ढंग के कपड़े. शाम को शराब—बिना सोडे के स्काच—पीने में संपत को कोई एतराज नहीं जबकि निर्मला जिन और टॉनिक लेने में कोई हर्ज नहीं समझती. सप्ताहांत में डिस्को जाना भी जैसे उनके लिए अनिवार्य है.

मद्रास अब मछुआरों के गांवों—जैसे. माइलापुर और त्रिप्लीकेन—का बड़ा समूह भर नहीं रह गया है. परंपरा और रूढ़िवादिता के प्रति वैसा आग्रह नहीं रहा और यह शहर सही अर्थों में एक महानगर बनकर उभरा है. एक न्यूरोलॉजिस्ट 39 वर्षीय डॉ. पृथिका चेरी, जो इसी शहर में जन्मी और पली हैं, कहती हैं, "दस या पंद्रह साल पहले जब कभी मैं मद्रास से बंगलूर जाती तो लगता मानो किसी गांव से शहर में जा रही हूं. मगर अब कोई फर्क नहीं नजर आता."

मद्रास में घुसते ही इसकी शहरी प्रौढ़ता के संकेत मिलने लगते हैं. दोमंजिले मकान गिराकर चार या पांचमंजिले फ्लैटों में तब्दील किए जा रहे हैं. अचल संपत्ति की कीमतें पिछले सात साल में दस गुना बढ़ गई हैं. मद्रास महानगर विकास प्राधिकरण के सदस्य सचिव एन.के. त्रिपाठी के मुताबिक 1981-82 में तीनमंजिली इमारतों की केवल 576 योजनाओं को मंजूरी मिली थी लेकिन 1987-88 के पहले छह महीनों में ही ऐसी 1266 योजनाएं मंजूर की जा चुकी हैं.

भीड़भाड़ वाली सड़कों से भी पता चलता है कि फुरसत के दिन अब नहीं रहे. शहर के परिवहन आयुक्त एस.टी. कासीराजन कहते हैं, "1976 में मद्रास में जितने दुपहिये वाहन थे, आज उससे 12 गुना ज्यादा हैं. यही हाल चार पहिये वाले वाहनों का रहा है. जाने-माने तमिल लेखक शिवसंकरी चंद्रशेखर शिकायत करते हैं, "मद्रास में कार आसानी से चला पाना अब संभव नहीं रह गया है."

एक मोटे अंदाज के अनुसार कामकाजी महिलाओं की संख्या पांच सालों में दुगुनी हो गई है. परंपरागत पुरुष वर्चस्व वाले क्षेत्रों में भी महिलाओं की संख्या बढ़ रही है. परंपरावादी अंग्रेजी दैनिक 'हिंदू' को ही लें. पहले वहां पुरुष ही पुरुष दिखते थे पर अब उसके उप-संपादकों में महिलाओं की अच्छी संख्या है. इसी तरह टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स में भी महिलाएं बढ़ गई हैं. सुंदरम क्लेटॉन के संयुक्त प्रबंध निदेशक गोपाल श्रीनिवासन कहते हैं, "टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स में लिए जाने वाले ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रशिक्षुओं में महिलाओं की संख्या दस प्रतिशत से कुछ ही कम रह जाएगी."

औसत पारिवारिक आय भी बढ़ी है और उनके पास खर्च करने को अब ज्यादा पैसा है. इसका बड़ा हिस्सा बाहर खाने में चला जाता है. शहर भर में 'फास्ट फूड' की दुकानें देखी जा सकती हैं. इनमें एक दर्जन तो पिछले साल ही खुलीं. 'केनोपी', एक साल पहले माइलापुर—मद्रास के सबसे ज्यादा परंपराप्रिय इलाकों में से एक—में भेलपुरी से शुरू हुई थी. अब यह रेस्तरां पांच गुनी ज्यादा बिक्री कर रहा है. नंगबक्कम हाई रोड पर चार साल पहले खुले 'केक्स ऐंड बेक्स' के 42 वर्षीय मालिक विशंभर निचाणी कहते हैं, "एक समय था जब रात नौ बजे के बाद कोई ग्राहक नहीं आता था. अब रात 11 बजे जाकर ही कहीं रेस्तरां बंद कर पाता हूं."

चीनी भोजन के रेस्तरां भी तेजी से बढ़ रहे हैं. दो सालों में ऐसे दर्जन भर रेस्तरां शुरू हुए. ऐसे ही एक कामयाब रेस्तरां 'रांगीज' के एक साझीदार जयकुमार गोविंदराज (25) के शब्दों में, "अब मैं अनेक पप्पनों (ब्राह्मणों के लिए स्थानीय शब्द) को बीफ (गोमांस) खाते देखता हूं." बदलाव के चलते थाई और मलेशियाई योजना वाले रेस्तरां के अलावा मेक्सिकन योजना का भी रेस्तरां खुला है.

ज्यादा समय नहीं हुआ जब एक औसत मद्रासी किसी पांचतारा होटल को श्रद्धा से

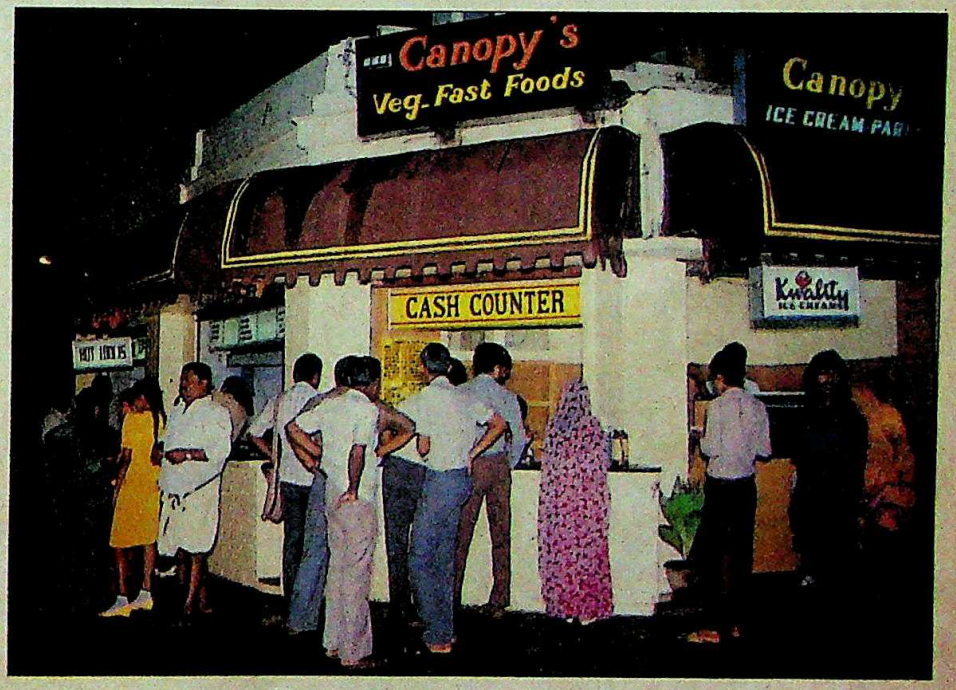

तैयार भोजन का बढ़ता प्रचलन; और महिलाएं कारों की स्टीयरिंग पर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ये सभी चिन्तायें हम पर छोड़ दीजिये...

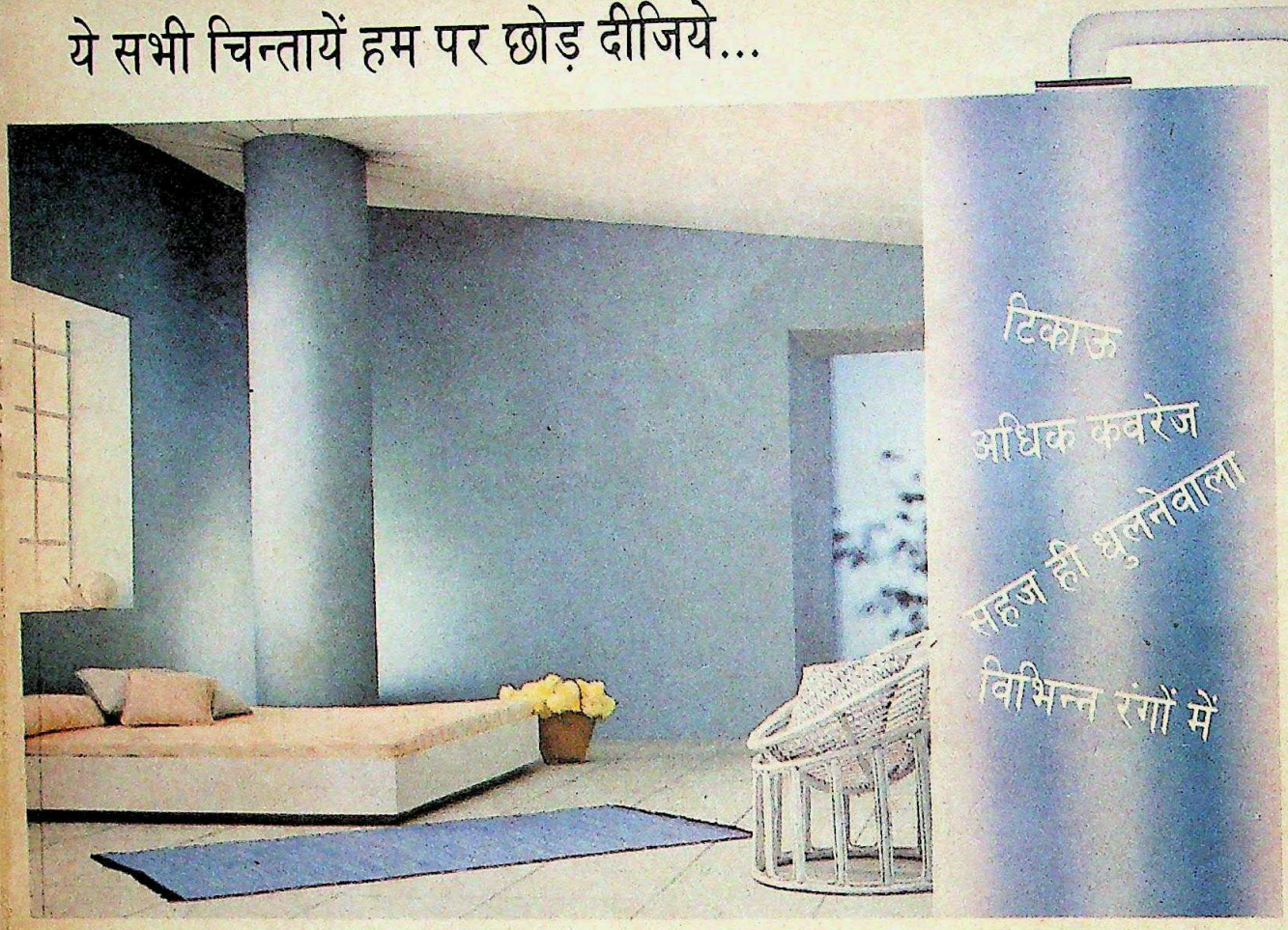

आपने ड्यूलक्स एक्रेलिक इमल्शन जो चुन लिया।

बस, उस ड्यूलक्स फ़िनिश का मजा लीजिये!

केवल ड्यूलक्स की विश्वव्यापी 'अग्रणी' पेन्ट तकनीक ही आपको एक संपूर्ण वॉल फ़िनिश दे सकता है—ड्यूलक्स एक्रेलिक इमल्शन। आपके रुपये का अधिक मूल्य। प्रति लिटर अधिक कवरेज देने वाला। बहुत से आकर्षक रंगों में उपलब्ध। और जो आसानी से धुले, फिर भी लगे हर बार नया!

दिखने में अद्‌भुत सुन्दर! आप हैरान रह जायेंगे कि एक एक्रेलिक इमल्शन इतनी शानदार फ़िनिश दे सकता है। लेकिन यही तो है ड्यूलक्स एक्रेलिक इमल्शन का जादुई कमाल। बेजोड़!

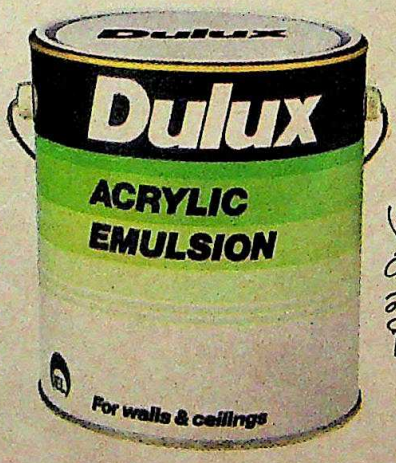

ड्यूलक्स का ये है कमाल नहीं इसकी कोई मिसाल!

IEL
IEL Limited

CLARION C-IELAE-3R

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

देखता और आगे बढ़ जाता था. मगर अब शहर में पांचवां पांचतारा होटल 'मद्रास ओबेराय' खुलने ही वाला है. 'चोला' के महाप्रबंधक 37 वर्षीय विजय खरे कहते हैं, "इसमें शक नहीं कि रूढ़िवादी संस्कृति बदल रही है. उदाहरणस्वरूप, हमारा अंदाज है कि चार पांचतारा होटलों में हर दोपहर 500 से ज्यादा लोग बुफे लंच लेते हैं. दो साल पहले के मुकाबले यह संख्या दुगुनी है."

पहनावे में यह बदलाव और ज्यादा झलकता है. टीटी मैप्स ऐंड पब्लिकेशंस का उदाहरण लें. इसके प्रबंध निदेशक एस. मुथैया याद करते हैं कि 1968 में उनके लगभग 70 कर्मचारियों में ज्यादातर धोती में या बहुत हुआ तो फटी सूती पैंट में आते थे. "तब उनमें अनेक को नंगे पांव आने में कुछ गलत नहीं लगता था. आज ज्यादातर कर्मचारी पोलिएस्टर की पैंट और महंगे जूते पहन कर दफ्तर आते हैं."

महिलाओं में यह फर्क और भी मुखर है. मद्रास में ही जन्मी-पली एक कला स्नातक 21 वर्षीया सुनीता जैन कहती हैं, "साड़ियों की जगह अब सलवार-कमीज और जींस ने ले ली है." अगर चोटियों की जगह विविध हेयर स्टाइल आ गए हैं तो सोने के बजाय प्लास्टिक के आभूषण चल पड़े हैं.

शहर भर में बुटीक दिखने लगे हैं. सबसे पुराने बुटीकों में से एक (सात साल पुराने) 'मेडमोइले सेल' की मालिक रीता लाल (33) बताती हैं कि उनकी दुकान में सबसे पहले साड़ी पहने महिलाएं आती थीं. फिर सकुचाती कॉलेज छात्राएं आईं, जिन्होंने सलवार-कमीज खरीदने की हिम्मत की. इसके बाद नवविवाहिता युवतियां आने लगीं और फिर भारी झिझक के बाद महिलाओं ने पश्चिमी तरीके के कपड़े खरीदने आरंभ किए.

परंपराएं तोड़ने में भारी साहस की जरूरत जरूर पड़ी लेकिन इसका लाभ भी हुआ. पांच साल पहले लता मोहन (तब वे 25 साल की थीं) ने माइलापुर जैसे रूढ़िवादी इलाके में ब्यूटी पार्लर खोला तो वहां की गृहिणियों के लिए यह जैसे अनहोनी थी. पार्लर के शुरू के कई महीने लता मक्खियां मारती रहीं. कोई महिला दुकान के आसपास भी नहीं फटकती थी. वे कहती हैं, "लेकिन अब हर शनिवार की दोपहर को इतनी भीड़ हो जाती है कि महिलाओं को लाइन लगानी पड़ जाती है."

स्थानीय लोगों के नजरिये में बदलाव को आखिर किस चीज ने गति दी? शायद सबसे ज्यादा असर दूसरे महानगरों से यहां

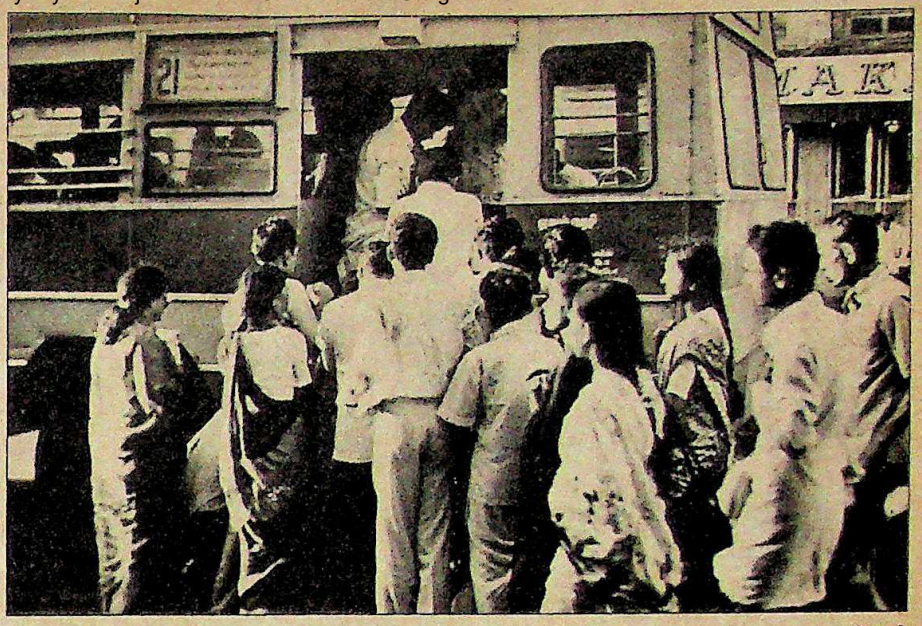

श्याम टेकवानी

काम पर जाती महिलाएं; और (नीचे) बुटीक में खरीदारी: झिझक मिटी

आए लोगों (खासकर उत्तर भारतीयों) का पड़ा. ये वे लोग थे जो बहुत घिचपिच के कारण बंबई को, और जमीन की आसमान छूती कीमत के कारण दिल्ली को छोड़ मद्रास की ओर मुड़े थे—इस उम्मीद में कि इस अपेक्षाकृत कम खर्चीले शहर में उन्हें हर तरह की सुविधा मिलेगी. बाहरी लोगों का आगमन 1980 के आसपास शुरू हुआ जिनमें कलकत्ता की 'अराजकता' से आतंकित लोग भी थे. आंकड़े मिलना मुश्किल है लेकिन एक अनुमान के मुताबिक दूसरे महानगरों से मद्रास आने वाले लोगों की संख्या हर साल 20-25 प्रतिशत बढ़ रही है.

उपभोक्ता सामग्री के प्रति भी नजरिया बदला है. मूसल, खरल और चक्की की जगह अब मिक्सी और वेट ग्राइंडर ने ले ली है. कारखानों के कामगार प्रेशर कुकर और मिक्सी लेकर गर्व महसूस करते हैं. मध्यम-वर्गीय परिवार कपड़ा धोने की मशीन खरीद रहे हैं. नौकरानियां पैसे बचाकर अक्सर छुट्टी के दिन किराये पर वीडियो लाकर फिल्में देखती हैं.

डिपार्टमेंटल स्टोर इस नए उपभोक्तावाद का लाभ उठाने में लगे हैं. बंगलूर का मशहूर 'नीलगिरी डेयरी फार्म' पांच साल पहले मद्रास आया और अब हर महीने के पहले हफ्ते में उसकी बिक्री प्रतिदिन एक लाख रुपए की है. हालांकि अभी बहुत लोगों की रुचि इसमें नहीं है, फिर भी रोजाना की बिक्री 12,000 रुपए से 15,000 रुपए के बीच घटती-बढ़ती रहती है.

डिपार्टमेंटल स्टोर्स को मान्यता मिलने

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लगी है, यह देख टीवीएस समूह ने पिछले महीने 'स्टॉप ऐंड शॉप' शृंखला की पांच दुकानें खोलीं. इनकी भी शुरुआत काफी अच्छी रही. इस शृंखला के प्रबंध निदेशक आर. बद्रीनारायण ने बताया, "इतने कम समय में ही हमारी बिक्री रोजाना प्रति दुकान 30,000 रुपए पहुंच गई है. शहर में ऐसे 20 स्टोर खोलने की हमारी योजना है जिनमें हर एक में 5000 उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध हो सकेंगी."

कंपनी के शुरुआती सर्वेक्षणों में यह तथ्य सामने आया है कि दूसरे महानगरों की तरह मद्रास में भी संयुक्त परिवार टूट रहे हैं. कामकाजी दंपतियों की संख्या बढ़ रही है और घरेलू नौकर मिलना मुश्किल होता जा रहा है. इसलिए हैरानी की बात नहीं कि 'स्टॉप ऐंड शाप' की बिक्री का छह फीसदी केवल तैयार खाद्य से आता है.

पारिवारिक ढांचे और खरीदारी की आदतों का अगर पश्चिमीकरण हो रहा है तो यही हाल यौन संबंधी मूल्यों का भी है. संकोच के जमाने लद गए. अब तो लड़कियां डेटिंग पर भी जाने लगी हैं. कभी किसी बस में महिला के बगल में बैठने भर से त्योरियां चढ़ जाती थीं. मध्य मद्रास में निजी क्षेत्र की एक फर्म में काम करने वाली 21 वर्षीय एस. सुधा कहती हैं, "बड़ी उम्र की महिलाएं तो अब पुरुषों से हाथ मिलाने में भी नहीं झिझकतीं. एक दशक पहले यह कोई सोच भी नहीं सकता था. और अगर अब कोई लड़की किसी लड़के के साथ दिख जाए तो लोग कूदकर इस नतीजे पर नहीं पहुंच जाते कि जरूर कोई चक्कर है."

कॉलेज परिसर में डेटिंग आम हो चली है. यौन समस्याओं के विशेषज्ञ डॉ. डी. नारायण रेड्डी के हाल के एक सर्वे से पता लगा कि मद्रास के 70 प्रतिशत कॉलेज छात्र सेक्स को गंदी चीज नहीं समझते और 68.25 प्रतिशत की राय थी कि इस पर खुलेआम बात की जानी चाहिए. 15.58 छात्रों ने तो समलैंगिक अनुभव से गुजरने की बात भी स्वीकारी. शहर के बीत चुके माहौल को देखते हुए यह चौंकाने वाली बात है. एक और सर्वेक्षण के अनुसार 42 प्रतिशत पुरुष शादी से पहले सेक्स का सुख भोग चुके हैं.

कुछ और मामलों में भी मद्रास गतिमान है. दो साल पहले जब एक पांचतारा होटल

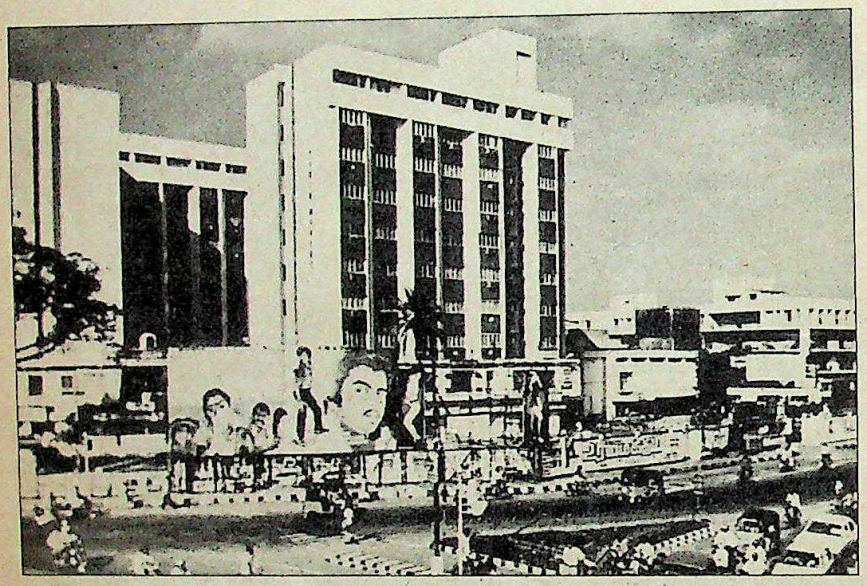

बहुमंजिली इमारतें: बदलाव की प्रतीक

ने डिस्को शुरू किया तो कुछ महीनों तक तो केवल पर्यटक और उत्तर भारत से गए लोग ही आते रहे. करीब 100 आगंतुकों में केवल दो ही मद्रासी होते थे. डिस्को में नियमित रूप से जाने वाला एक व्यक्ति बताता है, "अब उनमें 40 से 50 तक स्थानीय तमिल होते हैं." इसी से प्रेरित होकर पिछले पखवाड़े एक और पांचतारा होटल ने भी रविवार दोपहर का डिस्कोथे शुरू किया है.

एक सुस्त शहर अगर रफ्तार पकड़ रहा है तो उसके अनिवार्य तनाव भी बढ़ रहे हैं. महिलाएं क्योंकि आर्थिक रूप से ज्यादा स्वतंत्र होती जा रही हैं और पुरुष से पीछे नहीं रहना चाहतीं, सो तलाक के मामले भी अब ज्यादा होने लगे हैं. कई सालों से तलाक के मामलों में सालाना वृद्धि दर 5 प्रतिशत रही है लेकिन एक वकील के मुताबिक, "इस साल शहर में (सेशन और हाईकोर्ट में) तलाक के करीब 800 मामले दायर भी हो चुके हैं. मौजूदा संख्या ही पिछले वर्ष के मुकाबले 10 प्रतिशत ज्यादा है."

विकास अपने साथ तनाव-जनित रोग भी लाया है. अपोलो अस्पताल जिसने चार साल में ही अपना स्थान बना लिया है और जो 1200 से ज्यादा बायपास सर्जरी और 2500 ओपन हार्ट सर्जरी कर चुका है, के अध्यक्ष और हृदय रोग विशेषज्ञ 54 वर्षीय डॉ. प्रताप सी. रेड्डी बताते हैं, "केवल पिछले एक महीने ही हमारे पास तीन युवा अधिकारियों को दिल का दौरा वगैरह के मामले आए जो एक असामान्य बात है."

शहर एक दूसरे तरह के तनाव से भी जूझ रहा है. यह है टूटती परंपराओं को बनाए रखने की कोशिश करते बड़े-बूढ़ों और बदलाव को लालायित युवाओं के बीच का तनाव. कुछ मां-बाप अपने बच्चों की स्वच्छंद जीवन शैली को देख रूढ़ियों पर और भी दृढ़ हो गए हैं. उदाहरण के लिए, कृष्णस्वामी आयंगर के घर में उनका बेटा के. संपत महसूस करता है कि उनके पिता की जीवन शैली समय के अनुरूप नहीं है. लेकिन उसके पिता का मन अपने आसपास को देखकर कड़वाहट से भर गया है. वे कहते हैं, "यह सब पश्चिम का अशुभ प्रभाव है. ये आधुनिक युवा भगवान को याद न करके, मंदिर न जा करके, धूम्रपान और शराबखोरी करके और हिंदू धर्म के सिद्धांतों का पालन न करके जो पाप कर रहे हैं, इस सबका उन्हें फल भुगतना होगा."

आयंगर की बात ज़्यादा सख्त मालूम दे सकती है लेकिन उनकी उम्र के दूसरे लोग भी ऐसा ही सोचते हैं, हालांकि उनके विचार कुछ उदार हैं. मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एम.एम. इस्माइल (67) कहते हैं, "हम सादा जीवन और उच्च विचार के एकदम उलटी दिशा में जा रहे हैं." 83 वर्षीय एस.एच.ए. कृष्णन के शब्दों में, "शहर ज्यादा परिष्कृत, ज्यादा पश्चिममुखी और ज्यादा महानगरीय होता जा रहा है. यह सब तो चलो ठीक है; मगर इसके साथ ही निष्ठुरता और मूल्यों के प्रति लापरवाही भी आती जा रही है, यह सब नहीं होना चाहिए."

कृष्णन की बात में दम तो है लेकिन यह तो विकास की वह कीमत है जो हर शहर को चुकानी ही है. और जबकि मद्रासी अपने नए कपड़ों, रेस्तरां के लिए अगली रवानगी, सप्ताहांत पर नृत्य और अपनी ताजा खरीदारी को लेकर व्यस्त होंगे, कृष्णन और इस्माइल जैसे बहुत से लोगों की धारणाएं आगे ही आगे चलते जाने की इस दौड़ में दफन हो जाएंगी.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आज का शॉ वॉलेस

जहाँ दृष्टि बदले सृष्टि में

शॉ वॉलेस : उपक्रम के विविध आयाम ।

गोंद, जिलेटिन, जूते, खमीर, शराब, जहाजरानी, खेती के साधन... शताधिक वर्षों में पनपी गतिविधियों का प्रकाशपुंज ।

अब छाबरिया संगठन का एक अंश बन कर नई नई सीमाओं की ओर अग्रसर ।

तेल निकासी और उपकरण, भूकंपमापी सर्वेक्षण, कम्प्यूटर कन्सल्टेन्सी, सफ़ेद सीमेंट, बायो टेक्नॉलॉजी ।

उपक्रमों की दुनिया में एक नये युग की ओर बढ़ते कदम ।

TOWER
Crystal
Crystal
Crystal

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

चौधरी का चमत्कार

पिछले पखवाड़े गुजरात के मुख्यमंत्री अमर सिंह चौधरी की छवि को कुछ निखार मिला जब उन्होंने नर्मदा पर बनाए जाने वाले सरदार सरोवर बांध के निर्माण में सहायता देने के लिए सरदार सरोवर निगम के गठन की घोषणा की. इस घोषणा का लंबे समय से इंतजार था. यह घोषणा इसलिए भी स्वागतयोग्य है क्योंकि बांध के निर्माण के लिए राशि जुटाना कठिन हो गया था. 1980 में इसके निर्माण का अनुमानित खर्च 6000 करोड़ रुपए था जो ताजा अनुमान के अनुसार अब बढ़कर करीब 13,500 करोड़ रुपए हो गया है.

चौधरी

निगम की स्थापना 2000 करोड़ रुपए की अधिकृत शेयर पूंजी के साथ की जाएगी. बांडों के जरिये पैसा उगाहने की आशा की जा रही है. निगम आप्रवासी भारतीयों से भी पूंजी लगाने को कहेगा.

केंद्र से इस योजना की मंजूरी ले लेना चौधरी की एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि पार्टी के भीतर तथा बाहर हर स्तर पर उन पर हमले हो रहे हैं. 15 वर्ष बाद जब यह बांध बनकर तैयार हो जाएगा तो इससे सूखापीड़ित गुजरात के 5000 गांवों तथा 130 शहरी क्षेत्रों को पेयजल मुहैया कराया जा सकेगा.

भक्ति रस में डूबे बैंक

बैंक और भक्ति संगीत में भले ही कोई साम्य न हो लेकिन आंध्र प्रदेश में बैंकों ने भजनों को प्रायोजित करने का एक नया धंधा शुरू कर दिया है. आंध्र बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद तथा निजी क्षेत्र का व्यास बैंक मिलकर 15वीं शताब्दी के संत संगीताचार्य ताल्लयाका अन्नमाचार्य के भजनों, गीतों आदि के प्रचार-प्रसार वास्ते बने ट्रस्ट के लिए कोष इकट्ठा कर रहे हैं. भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति में रचित अन्नमाचार्य के 12,000 भजन तांबे की पट्टियों पर खुदे हुए हैं.

नई योजना के अंतर्गत उपरोक्त चार बैंकों की, देश अथवा विदेश की किसी भी शाखा से 350 रुपए में इन भजनों के चार कैसेट, फीचर फिल्म का एक ऑडियो कैसेट, दो पुस्तकें, भगवान वेंकटेश्वर की एक फोटो, अन्नमाचार्य की धातु की एक मूर्ति और एक चाबी का छल्ला भी मिलेगा. अन्नमाचार्य ट्रस्ट के प्रबंध न्यासी बी.ए.वी. शांडिल्य का कहना है कि इन सब पर केवल 150 रुपए खर्च होंगे. बिक्री के मुनाफे से एक सभागार, एक नृत्य तथा संगीत स्कूल, हैदराबाद में एक शोध केंद्र और पांच अन्नमाचार्य सांस्कृतिक केंद्र खोले जाएंगे. आशा भोंसले, वाणी जयराम, एस.पी.बालासुब्रमण्यम तथा यशुदास जैसे गायकों ने इन भजनों को अपना सुर दिया है. इसलिए योजना की सफलता में कोई संदेह नहीं.

नागेंद्र राव

अन्नमाचार्य की धातु की मूर्ति

माफिया किंग को अंतिम विदाई

बंबई माफिया गिरोह के कुख्यात दादा 62 वर्षीय मुनिस्वामी वरदराजन मुदालियार उर्फ 'वरदा' का अंतिम संस्कार पिछले दिनों किसी स्थानीय नेता के से सम्मान के साथ किया गया. एक समय था जब उसके गिरोह का आतंक पूर्वी बंबई पर छाया रहता था. बंबई पर उसके 'राज' को 1985 में सफलतापूर्वक चुनौती दी थी पुलिस उपायुक्त वाई.सी. पवार ने. उसके गिरोह को छिन्न-भिन्न कर दिया गया तो वह मद्रास चला गया. वहीं 2 जनवरी को दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई. कहा जाता है कि उसने तस्करी और गोदी से माल चुराने का 'विशाल व्यवसाय' हाजी मस्तान से विरासत में पाया था. उसकी मौत की खबर सुनकर मस्तान भी मद्रास गया. वहां से एक चार्टर्ड विमान द्वारा वरदराजन का शव बंबई लाया गया.

नामस भोजानी

वरदा को श्रद्धांजलि: अपराध की महिमा

बताया जाता है कि कई इंका नेता उसके करीबी रहे क्योंकि वह उन्हें चुनावों के लिए पैसे दिया करता था. नगर निगम के कई पार्षद अंतिम दर्शन के लिए उसके घर गए. शव यात्रा में उसके कई ऐसे पुराने साथी थे जो बंबई छोड़ चुके थे.

मुख्यमंत्री का पुत्र-मोह

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बीरबहादुर सिंह देहरादून से कुछ विशेष मोहित लगते हैं. सितंबर 1985 से नवंबर 1987 के बीच उन्होंने इस शहर का 37 बार दौरा किया. दौरों का मुख्य कारण उनका बेटा है, जो यहां के प्रतिष्ठित दून स्कूल में छठी क्लास का छात्र है. मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि करीब 15 बार बीरबहादुर सिंह के बेटे ने भी उनके साथ विमान में यात्रा की.

बीरबहादुर

जब-जब मुख्यमंत्री अपने बेटे से भेंट करने जाते हैं तब-तब देहरादून के जिला प्रशासन को सुरक्षा का व्यापक प्रबंध करना पड़ता है. जिले के कलेक्टर, एस.पी. तथा कई बार तो गढ़वाल के कलेक्टर तक को इस दौरान मौजूद रहना पड़ता है.

पहले लखनऊ सचिवालय में मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों का ब्यौरा देने के लिए रोजाना एक सरकारी सूचना प्रसारित की जाती थी. लेकिन हाल के महीनों में वे चुपचाप बिना किसी को खबर किए देहरादून की अपनी यात्रा पूरी कर आते हैं. शायद वे रवैया बदल रहे हैं.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

टाटा की ओर से टाइटन क्वार्ट्ज़

ऐसी घड़ियों के लिए अब आपको यूरोप, जापान अमरीका या किसी ड्यूटी-फ़्री दुकान में जाने की ज़रूरत नहीं. इन्हें आपके शहर में पेश कर रहे हैं टाइटन.

आकर्षक, पतली और बहुत बारीक इंजीनियरिंग से सजी संवरी टाइटन घड़ियां दुनिया की सबसे अच्छी घड़ियों की बराबरी में आ सकती हैं.

टाइटन की **अंतर्राष्ट्रीय किस्मों** में ऐसी घड़ी ज़रूर है, जो आपके लिए बिल्कुल सही है. शान और रूप का अनोखा संगम. लेदर के साथ गोल्ड वाली टाइटन या सिर्फ़ गोल्ड की चमकदमक वाली लीजिए. अगर सिर्फ़ स्टील वाली चाहिए तो वो भी हाज़िर. या फिर आजकल के ज़माने वाली कोई और टाइटन चुन लीजिए.

औरतों के लिए निहायत खूबसूरत डिज़ाइनों वाला कलेक्शन, जिसमें स्टाइल, वरायटी और रंगों पर विशेष नज़र रखी गई है. इतना ही नहीं, टाइटन के पास लेडीज़ डेट और डे-डेट घड़ियों की सबसे बड़ी श्रेणी मौजूद है.

टाइटन क्वार्ट्ज़ अपनी बराबरी में आ सकनेवाली सबसे अच्छी, चाबी से चलने वाली या आटोमैटिक घड़ियों से **६० गुना ज़्यादा सही** है.

हर टाइटन क्वार्ट्ज़ पर क्वालिटी और विश्वसनीयता की **टाटा गारण्टी** है.

अपने शहर की किसी अच्छी घड़ी की दुकान में जाइए और पसंद कीजिए कोई टाइटन क्वार्ट्ज़ अपने लिए या अपनों के लिए.

TITAN
QUARTZ

शानदार स्टाइल वाली टाइटन घड़ियां केवल रु. ३६२ से रु. ११३७ (बिक्री कर और स्थानीय कर अलावा) तक में मिलती हैं.

अपने लिए, अपनों के लिए

टाइटन वाचेज़ लिमिटेड
सोना टावर्स, ७१ मिलर रोड, बंगलोर ५६० ०५२.

OBM/1901/HN

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

एक मज़बूत सतह-समतल और सुंदर, चाहे जैसे हो इस्तेमाल, वर्षों तक वैसी की वैसी-बे असर!

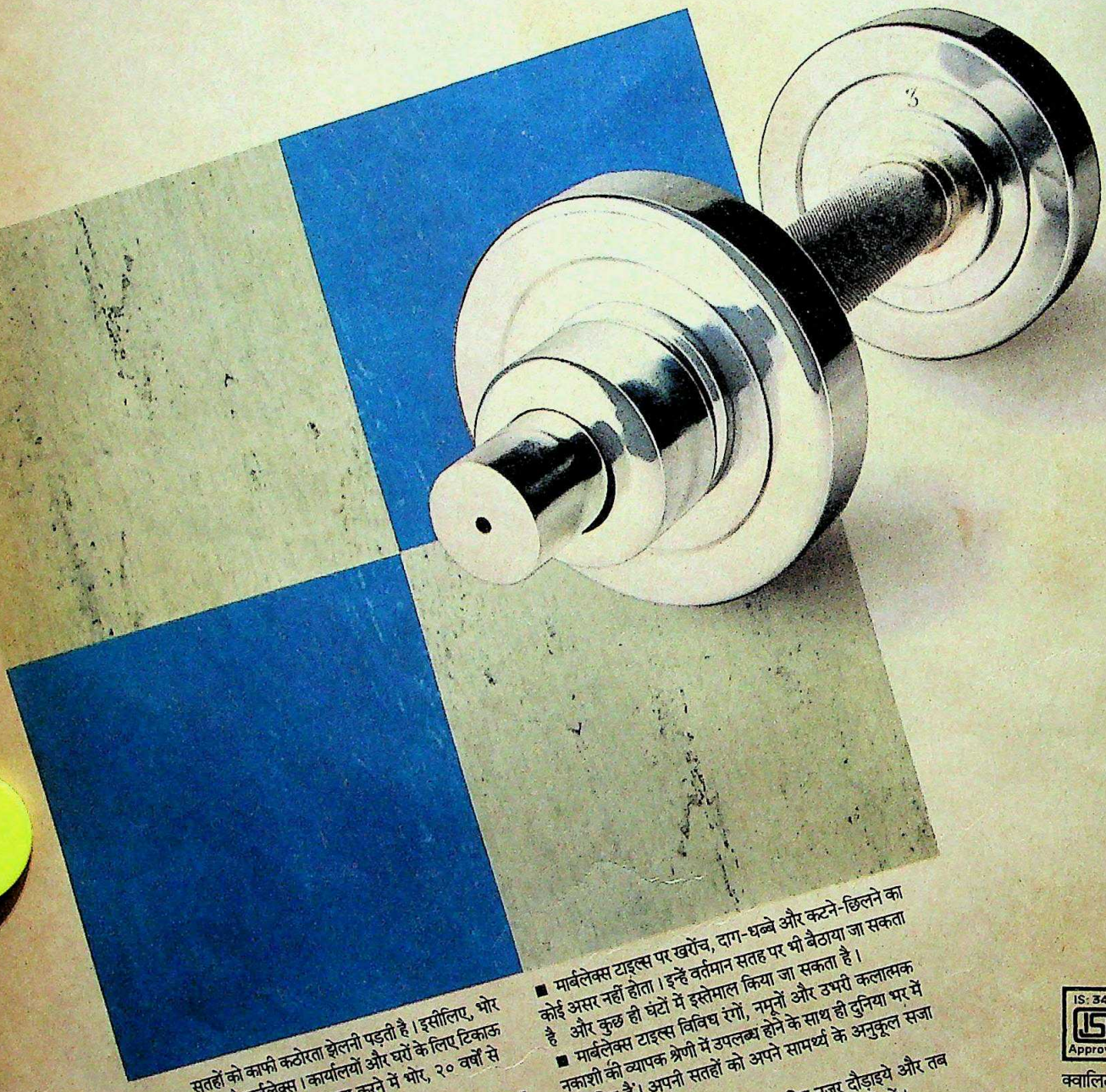

सतहों को काफी कठोरता झेलनी पड़ती है। इसीलिए, भोर ने आपको दिया है मार्बलेक्स। कार्यालयों और घरों के लिए टिकाऊ और सजीली सतहों का साधन प्रदान करने में भोर, २० वर्षों से अग्रणी रहे हैं।

■ मार्बलेक्स का वज़न, परम्परागत मोज़ैक टाइल्स की तुलना में सात गुना कम है और खर्च? इसके आजीवन उपयोगी रहने की दृष्टि से विचार करें तो निश्चित ही उससे बहुत कम जितना आपको लगता है।

■ मार्बलेक्स टाइल्स कम से कम देख-रेख में भी २० वर्षों से भी ज्यादा टिकते हैं। नियमित सफाई या वैक्सिंग की जाये तो वर्षों तक इनमें नयापन भी बना रहता है।

■ मार्बलेक्स टाइल्स पर खरोंच, दाग-धब्बे और कटने-छिलने का कोई असर नहीं होता। इन्हें वर्तमान सतह पर भी बैठाया जा सकता है और कुछ ही घंटों में इस्तेमाल किया जा सकता है।

■ मार्बलेक्स टाइल्स विविध रंगों, नमूनों और उभरी कलात्मक नकाशी की व्यापक श्रेणी में उपलब्ध होने के साथ ही दुनिया भर में लोकप्रिय हैं। अपनी सतहों को अपने सामर्थ्य के अनुकूल सजा सकते हैं आप।

आज ही अपनी सतहों पर फिर नज़र दौड़ाइये और तब सोचिए— सब से पहले— भोर मार्बलेक्स के बारे में।

IS: 3461 ISI Approved

क्वालिटी के इस निशान को देखिए

कुछ ही घंटों में उपयोग योग्य

BHOR MARBLEX

ऐसी सतह जो अविराम, करती रहे काम!

भोर इंडस्ट्रीज़ लि., ■ ३९२, वीर सावरकर मार्ग, बम्बई ४०० ०२५. टेलि. ४३०२२४१ ■ ४/२४-ए, आसफ़ अली रोड, नई दिल्ली ११० ००२. टेलि. २७१५६३/२६९८१३ ■ अंबल बिल्डिंग, पहली मंज़िल, ७२७, पठारे रोड, ऑफ़ माउण्ट रोड, मद्रास ६०० ००६. टेलि. ८११२७४ ■ १०/ए, हो ची मिन्ह सरणी, कलकत्ता ७०० ०७१. टेलि. ४४९१९४

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सवारी हो तो एटलस. जो करे हवा से बातें

5-स्पीड वाली नई स्पोर्टस्टर

- सर्वोपेन्टा प्रणाली से युक्त आयातित सन रेस गीयर सिस्टम
- गीयर 1 तथा 2: सवार हो जाइये और कीजिए हवाई सफ़र शुरू. सामने की हवा हो या कोई पहाड़ी सफ़र

गीयर 3: दौड़ाइये तेजी से, समुद्र तट की राहों पर

- अब आइए चौथे गीयर में और बढ़ाइए अपनी स्पीड
- गीयर 5: और दौड़ाइए अपनी साइकिल एक चैम्पियन की तरह
- विशेषरूप से डिज़ाइन किया गया फ्रेम! सुगम गीयर परिचालन के लिए
- एक्रीलिक: पोलीक्रोमेटिक रंग—गहरा जामुनी (बरगंडी) नीला, कत्थई, सलेटी

एक और सनसनीखेज़ साइकिल

ऐच्छिक सुविधा: विशिष्ट टैकोमीटर
5 स्पीड वाली स्पोर्टस्टर चुनिए या स्पोर्टस्टर

Atlas
«FUNFLEET»

विश्व श्रेणी विश्व शैली की साइकिलें

CONTRACT AC—271/87/HIN

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आखिर क्यों ज्यादा से ज्यादा लोग शादी-ब्याह के अवसर पर बीनाटोन क्वार्ट्ज टी.वी. ही उपहार में दे रहे हैं... ।

...सामंजस्य के लिए जिसकी गारंटी है।

अपने प्रिय से प्रिय व्यक्ति को दीजिए वह उपहार जो सर्वोत्तम हो। और अनूठे बीनाटोन क्वार्ट्ज टी वी से बेहतर उपहार भला क्या हो सकता है। रंगों की मोहकता तथा तस्वीर की स्पष्टता का बेमिसाल सामंजस्य और पिक्चर ट्यूब पर 3 साल की गारंटी भी। अपने निकटतम रंगीन/ब्लैक ऐण्ड व्हाइट टी वी के डीलर के यहां बीनाटोन के विविधतम मॉडलों को देखिए।

एक ऐसा उपहार जिसके लिए आप हमेशा याद किये जाएंगे।

बीनाटोन के सभी उत्पादनों को मास्टरकेयर का सहारा प्राप्त है जो बस एक फोन करते ही देशव्यापी बिक्री-बाद-सेवा प्रदान करते हैं।

Binatone

बनावट बेमिसाल, साथ निभाए सालोंसाल

बीनाटोन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लि., 23/4788-90 अंसारी रोड, दरियागंज, नयी दिल्ली-110002.

Arma Communications

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कर्ताधर्ता नदारद

कार्मिक विभाग और कई मंत्रालयों के बीच चल रही लंबी खींचातानी के कारण सरकारी उपक्रमों के निदेशक स्तर की 50 से भी अधिक नियुक्तियां अधर में लटकी हुई हैं. इनमें दर्जन से भी अधिक पद मुख्य प्रबंधकों के ही हैं. पिछले तीन महीनों में कार्मिक विभाग विभिन्न मंत्रालयों की सिफारिशों को अस्वीकार कर चुका है या जानबूझ कर उनकी नियुक्ति में देर लगा रहा है. हिंदुस्तान एअरोनॉटिक्स लिमिटेड, खनिज तथा धातु व्यापार निगम, राज्य व्यापार निगम, भारतीय पर्यटन विकास निगम के मामले में तो उन प्रत्याशियों को भी अयोग्य करार दे दिया गया जो सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड के माध्यम से चुन कर आए थे. मारुति उद्योग के प्रबंध निदेशक आर.सी. भार्गव, जिनका तीन वर्ष का कार्यकाल पिछले जून में ही समाप्त हो गया था—दिहाड़ी पर काम कर रहे हैं.

छाबरिया के छक्के जारी

कई कपनियों पर दनादन कब्जा जमा चुकने के बाद छाबरिया बंधु अब नए कारोबार की शुरुआत करने जा रहे हैं. 200 करोड़ रुपए की लागत से गुजरात में टायर कंपनी बनाने की उनकी योजना की चर्चा सब जगह हो चुकी है. अब छाबरिया के नियंत्रण में आई शॉ वैलेस कंपनी निर्माण के कारोबार में हाथ डाल रही है. शराब, खमीर और कीटनाशक बनाने वाली यह कंपनी अपनी नई योजना पर 25 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है. इस कंपनी के पास कलकत्ता में काफी जमीन है और नई—शॉ वैलेस प्रापर्टीज—कंपनी इस जमीन पर महंगी बहुमंजिली इमारतें बनाएगी. इस बीच इसकी सहयोगी कलकत्ता एंटरप्राइजेज डिटर्जेंट और टुथपेस्ट बनाने जा रही है. इस पर 10 करोड रुपए खर्च होंगे.

पालने में योजना

ग्रिंडलेज बैंक और क्रेडिट कैपिटल जैसी जो निजी कंपनियां 'वेंचर पूंजी' या नई कंपनियों को पैसा देने का कारोबार शुरू करना चाहती थीं, वे मुश्किल में पड़ गई हैं. पिछला अनुभव या पूंजी न होने से वित्त मंत्रालय उनकी योजनाओं को मंजूरी नहीं दे रहा है. ग्रिंडलेज बैंक की 10 करोड़ रुपए उठाने की योजना और क्रेडिट कैपिटल की पूंजी उठाने की योजना को साल भर से मंजूरी नहीं मिली है. वित्त मंत्रालय की आपत्ति काम शुरू न करने की है. पर इन संस्थाओं का कहना है कि बिना पूंजी के वे बाजार में उतरकर साख नहीं बना सकते. पिछले अक्तूबर में क्रेडिट कैपिटल ने शेयरों की निजी स्तर पर बिक्री करके बाद में लोगों के पास पूंजी के लिए जाने की पेशकश की थी. अभी तक सरकार इन तर्कों से प्रभावित नहीं हुई है.

सम्मेलनों का ब्यूरो

सरकार 'इंडियन कन्वेंशन प्रमोशन ब्यूरो' बनाने जा रही है. यह ब्यूरो देश में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा. वैसे यह धंधा आजकल जोरों से चल रहा है और 1987 में भारत में करीब 500 अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुए. 1984 में ऐसे 334 सम्मेलन हुए थे. ऐसे में एक एजेंसी का ख्याल आया जिसकी सदस्यता ट्रेवल के धंधे, एअरलाइंस, व्यापार संगठनों वगैरह के लिए खुली रहेगी. भारत 'इंटरनेशनल कन्वेंशंस ऐंड कांफ्रेंसेज़ एसोसिएशंस' का सदस्य है. इस संगठन की एक भारतीय शाखा भी है पर उसकी सदस्यता सिर्फ अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों तक सीमित है. उम्मीद है यह ब्यूरो इस साल काम शुरू कर देगा.

चाय के प्याले में उफान

चाय के 'प्याले' में उफान आया है. 1987 चाय उद्योग के लिए सबसे अच्छा साबित होने की उम्मीद है. इस साल 66 करोड़ किलोग्राम चाय पैदा होने की संभावना है. 1985 में ऐसा उफान आया था (देखें चार्ट). पर उसके बाद पूर्वोत्तर में बुरे मौसम के कारण उत्पादन गिर गया. 1985 में निर्यात भी 22.44

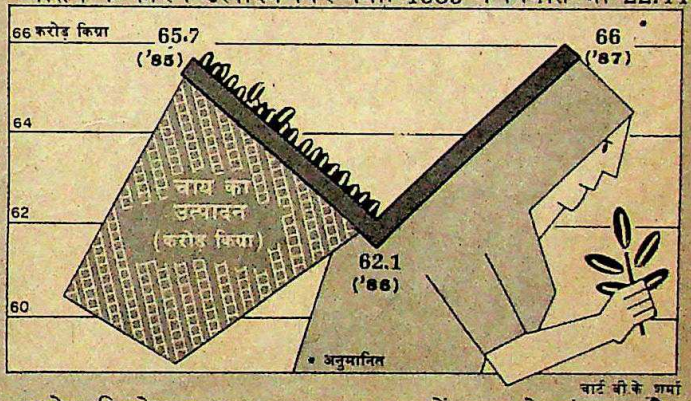

चार्ट बी.के. शर्मा

करोड़ किलोग्राम हुआ था. पर 1987 में चाय के अंतरराष्ट्रीय बाजार में बहुत तेजी नहीं थी और इस साल निर्यात 20 करोड़ किलोग्राम से थोड़ा ही ऊपर जाने की संभावना है. इसलिए सरकार दार्जिलिंग लेबल के प्रचार और अधिक कमाई वाली डिब्बाबंद चाय बेचने पर जोर दे रही है. ब्रिटेन में इसके लिए विज्ञापन अभियान साची ऐंड साची चलाएगी.

अमेरिकी दिलचस्पी

पिछले साल-दो-साल से कई बड़ी अमेरिकी कंपनियों ने भारत में सस्ते व कुशल कारीगरों की उपलब्धता भुनाने के लिए काफी दौड़धूप की है. इनमें वेस्टिंगहाउस और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स भी शामिल हैं. कई दूसरी कंपनियों ने भारतीय बाजार में दिलचस्पी दिखाई है. जनरल मोटर्स ने भारत सरकार के सामने अनौपचारिक प्रस्ताव रखा है कि वह उसे अपने यहां से सामान लाने और यहां तैयार करके माल वापस खरीद लेने की अनुमति दे. यह प्रस्ताव 1987 के मध्य में वाशिंगटन गए भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल की बैठक में रखा गया और भारत सरकार को भी इसकी खबर दी गई है. जनरल मोटर्स मनमाने निर्यात की आजादी चाहता है लेकिन यह बात न तो सरकार के गले उतरती है न उद्योग जगत के लोगों के. फिर इस भारी-भरकम ऑटोमोबाइल कंपनी ने अपने प्रस्ताव में तब्दीली की पर अभी तक सरकार की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तेजरफ्तार रेलगाड़ियां

हकीकत में बदलता सपना

बुलेट ट्रेनों के आने से रेलवे में क्रांतिकारी परिवर्तन की उम्मीद

अगर आप दिल्ली के कोई व्यापारी हैं और आज रात बंबई में आपको किसी डिनर पर पहुंचना है, तो आप क्या करेंगे? आप तड़के चार बजे ऊंघते हुए उठेंगे और सुबह की फ्लाइट पकड़ने भागेंगे. आज यह स्थिति जरूर है लेकिन चार साल बाद आप शायद सुबह का नाश्ता करके ट्रेन से रवाना होंगे और रात के खाने पर बंबई पहुंच जाएंगे.

कारण: नई तरह की तेजरफ्तार रेलगाड़ियां जल्दी ही पटरियों पर दौड़ने वाली हैं. चार महानगरों के बीच ये रेलगाड़ियां 160 किमी प्रति घंटे—राजधानी एक्सप्रेस की औसत गति से कम-से-कम 60 किमी ज्यादा रफ्तार से दौड़ेंगी. कम दूरी के, दिल्ली-आगरा-कानपुर जैसे रूटों पर जापानी बुलेट ट्रेन किस्म की ट्रेनें 200 किमी की रफ्तार से चलेंगी. जापान की एक सलाहकार फर्म इस बाबत भारतीय रेलवे को अपनी रिपोर्ट भी दे चुकी है. हालांकि अभी तक विशेषज्ञ इस खर्चीले प्रस्ताव का आकलन ही कर रहे हैं.

यही नहीं, नई ट्रेनें पतली, लंबी और—महत्वाकांक्षी कंप्यूटरीकरण कार्यक्रम की मदद से—ज्यादा सुरक्षित होंगी. उदाहरण-स्वरूप कुछ डिब्बों में स्वचालित दरवाजे और प्लास्टिक की सीटें होंगी. रेलवे की सलाहकार शाखा 'रेल इंडिया टेक्निकल ऐंड इकॉनॉमिक सर्विसेज' (आरआईटीईएस) के प्रबंध निदेशक आर. पार्थसारथी पुष्टि करते हैं, "ये डिब्बे पतले होंगे. बेहतर सस्पेंशन सिस्टम से झटके कम लगेंगे, और वर्तमान डिब्बों की अपेक्षा ज्यादा आरामदेह होंगे."

तेजरफ्तार ट्रेनें तो देश की पुरानी पड़ चुकी रेल व्यवस्था के नवीकरण के 45,000 करोड़ रुपए वाले कार्यक्रम का केवल एक पहलू हैं. इस राशि का 40 प्रतिशत हिस्सा पटरियां बदलने और उनके बिजलीकरण पर खर्च होगा. इसके अलावा भी कई उल्लेखनीय बातें हैं:

► एक इलेक्ट्रॉनिक सिगनल प्रणाली और कंप्यूटरीकृत माल परिवहन.

► एक रेडियो संचार प्रणाली जिससे, दूसरी चीजों के अलावा, यात्री ट्रेन में यात्रा के दौरान ही टेलीग्राम बुक कर सकेंगे और ड्राइवर का कंट्रोल रूम से सीधा संपर्क रहेगा.

► 150 करोड़ रुपए का एक कंप्यूटरीकृत रिजर्वेशन नेटवर्क जो सभी बड़े शहरों को जोड़ेगा. इस सदी के अंत तक इसमें 31 शहर जुड़ जाएंगे (नक्शा देखें).

► एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली जो गलती से सिगनल पार कर जाने वाले ड्राइवर को इसकी चेतावनी देगी.

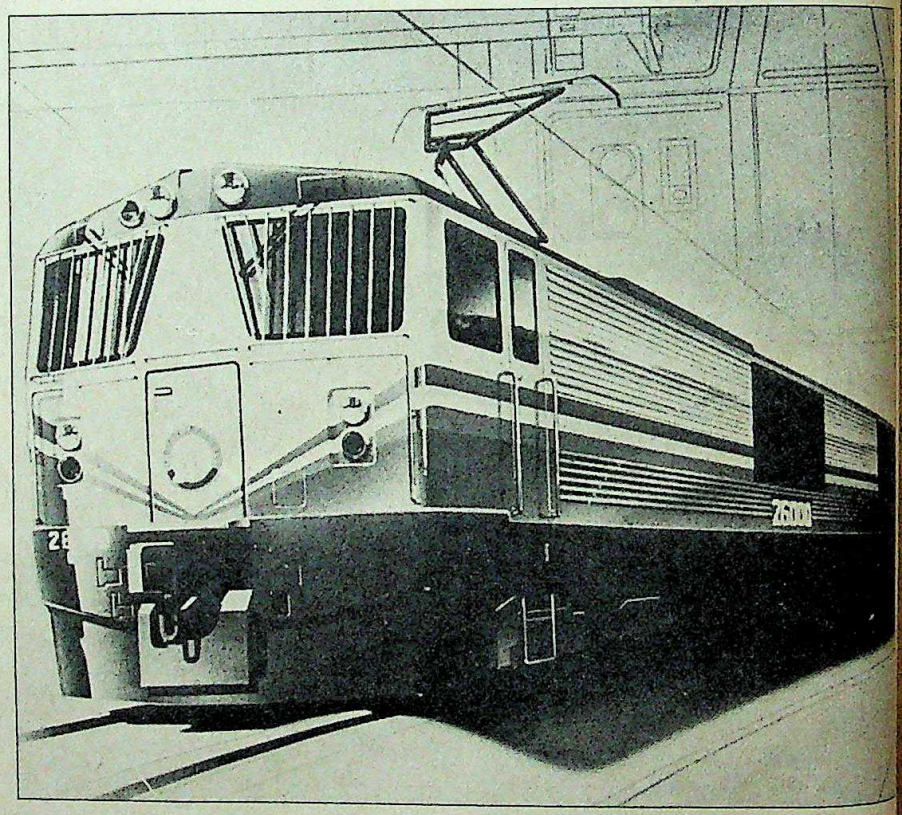

तेजरफ्तार रेलगाड़ियां तो देश की पुरानी पड़ चुकी रेल व्यवस्था के आधुनिकीकरण के 45,000 करोड़ रुपए वाले कार्यक्रम का एक पहलू भर हैं

ज्यादा जोर तेजरफ्तार और लंबी यात्री व मालगाड़ियों पर है. यात्री ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने का मतलब है कि मालगाड़ियों की रफ्तार भी मौजूदा 75 किमी से बढ़ाकर 100 किमी करनी पड़ेगी. अन्यथा तेज-रफ्तार यात्री ट्रेनों का माल-वहन पर दुष्प्रभाव पड़ेगा जबकि पिछले साल रेलवे के कुल राजस्व—4751 करोड़ का 67 प्रतिशत माल ढुलाई से ही मिला.

इस सबके लिए ज्यादा शक्तिशाली इंजनों की जरूरत होगी. विश्वस्तरीय खोज-बीन के बाद रेलवे स्वीडन और जापान से डीजल और बिजली के 18 इंजन आयात कर रहा है. टेक्नालॉजी हस्तांतरण समझौतों के तहत अंततः ये इंजन देश में ही बनाए जाएंगे. आयातित इंजन इसी साल किसी समय पटरियों पर दिखने लगेंगे. 40 दूसरे इंजनों के लिए भी अंतरराष्ट्रीय टेंडर मांगे गए हैं. कुल मिलाकर इन इंजनों पर 290 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है.

रेलवे अधिकारी दावा करते हैं कि यह पैसा बेकार नहीं जाएगा. रेलवे बोर्ड सदस्य वी.सी.वी. चेनुलु दलील देते हैं, "इन इंजनों से ऊर्जा खर्च में 7 से 10 प्रतिशत तक कटौती होगी." दूसरे, 6000 हार्सपावर वाले ये इंजन वर्तमान इंजनों के मुकाबले ज्यादा भारी व अधिक डिब्बों वाली ट्रेनें खींच सकेंगे.

सदी के अंत तक रेलवे को अनुमानित 400 अरब टन प्रति किलोमीटर माल ढोने

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

होगा और यात्रियों की संख्या भी तब तक दुगनी यानी 2 करोड़ यात्री प्रतिदिन हो जाएगी. इसका एक विकल्प यह है कि पटरियों की लंबाई दुगनी की जाए. लेकिन रेल अधिकारियों के मुताबिक पटरी बिछाने पर कुल 62,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे. रेलवे बोर्ड अध्यक्ष आर.के. जैन कहते हैं, "एक ही उपाय बचता है कि तकनीक में सुधार करके मौजूदा पटरियों का ही और प्रभावी इस्तेमाल किया जाए." अंततः रेल-गाड़ियों की तेज गति और बोगियों के अधिकाधिक प्रयोग की आवश्यकता ने कुछ दूसरे क्षेत्रों जैसे—संचार, सिगनल और सुरक्षा उपायों में भी परिवर्तनों को प्रोत्साहित किया है.

दूसरे क्षेत्रों में भी परिवर्तन आरंभ हो गए हैं. भिलाई इस्पात कारखाने ने भारी रेल पटरियों का निर्माण आरंभ कर दिया है. नई तेज गति की गाड़ियों के लिए डिब्बों के भी ढांचों में परिवर्तन की आवश्यकता पड़ेगी. इसलिए रेलवे अधिकारी विदेशों में नए डिजाइनों की तलाश कर रहे हैं. इस वर्ष कपूरथला कारखाने में नए डिब्बों का निर्माण आरंभ हो जाएगा. कुछ और नए प्रयोग भी किए जा रहे हैं. देश भर में 21 बड़े रेलवे स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक सूचना पट्ट लगवाए जाएंगे. फिलहाल दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 20 करोड़ रुपए की लागत से लगाए जा रहे इस सूचना पट्ट पर शहर के 30 किलोमीटर तक के दायरे में पहुंचने वाली रेलगाड़ियों के आने का सही समय प्रसारित किया जाएगा.

इसके अलावा मुगलसराय और नई दिल्ली के बीच 14 करोड़ रुपए की लागत से एक 'रेल रेडियो संचार प्रणाली' आरंभ की जा रही है. इसके द्वारा इंजन चालक रेलवे स्टेशनों तथा यात्रियों से संपर्क बनाए रख सकेंगे. तमिलनाडु में तो एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर एक कंप्यूटरीकृत सिगनल प्रणाली शुरू भी की जा चुकी है. यह यंत्र न केवल कर्मचारियों को गलत सिगनलों से आगाह कराता है, बल्कि सिगनलमैन द्वारा दिए गए सभी निर्देशों को रिकार्ड भी करता है ताकि कहीं कोई खामी न रह जाए.

बंबई की उपनगरीय रेलवे लाइन पर 5 करोड़ रुपए की लागत से देश में बने एक यंत्र पर प्रयोग किया जा रहा है. यह यंत्र इंजन चालकों को आगे आने वाले सिगनलों का पूर्व संकेत दे देता है. यदि गलती से चालक सिगनल को अनदेखा कर दे तो यह यंत्र गाड़ी में ब्रेक लगा देता है.

स्पष्ट है कि ये सारे प्रयास मानवीय गलतियों को कम करने के लिए किए जा रहे हैं जिसकी संभावना तब अधिक होगी जब गाड़ियों की गति बढ़ जाएगी और एक ही लाइन पर कई गाड़ियां चला करेंगी.

आरआईटीईएस के पार्थसारथि का कहना है, "पटरी तथा तेज गति के बेहतर प्रयोग से मानवीय गलतियों को यंत्रीकरण के जरिये ही सुधारा जाना चाहिए."

इस तकनीकी क्रांति से कम लागत पर अधिक आय प्राप्त करने जैसे कई ठोस परिणाम हासिल किए जा सकते हैं, उदाहरण के तौर पर रेलवे अधिकारियों का विश्वास है कि 1200 करोड़ रुपये के विवादास्पद माल ढुलाई कंप्यूटरीकरण कार्यक्रम से कार्यकुशलता बढ़ेगी. इससे माल ढुलाई कार्यक्रम में 15 प्रतिशत की वृद्धि होगी. सखलानी मानते हैं कि इससे मरम्मत का काम और कर्मचारियों का प्रबंधन सुगमता से हो सकेगा. इस प्रणाली से यात्री गाड़ियों को भी ठीक समय पर चलाने में सहायता मिलेगी.

इस नए आधुनिकीकरण कार्यक्रम से कई समस्याएं भी जुड़ी हैं—उदाहरण के तौर पर माल ढुलाई के कंप्यूटरीकरण की लागत को लेकर एक नया बावेला खड़ा हो गया है. इलेक्ट्रानिक विभाग का कहना है कि इस कार्यक्रम की लागत—1600 करोड़ रुपए—में 500 करोड़ रुपए महज इसलिए अधिक लगे कि इस व्यवस्था में उपग्रह के बजाय माइक्रो-वेव संचार व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है. आखिर पिछले महीने हुए एक समझौते के अंतर्गत इस कार्यक्रम में उपग्रह और माइक्रो-वेव संचार व्यवस्था, दोनों का उपयोग करने की बात तय कर ली गई है. इससे लगभग 400 करोड़ रुपए की बचत होगी.

कम-से-कम एक वरिष्ठ रेल अधिकारी ऐसा तो है जो निजी तौर पर ऐसी तेज गति की रेल गाड़ियों के विरुद्ध है. "तेज गति की रेल-गाड़ियां महज एक नाटकबाजी हैं. कर्मचारियों के, जो वास्तव में किसी क्षेत्र में परिवर्तन लाते हैं, लिए तो कुछ विशेष किया ही नहीं जा रहा," वे शिकायत के लहजे में कहते हैं. रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष प्रकाश नारायण मानते हैं कि "यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाएं वाकई निम्न दर्जे की हैं. इस दिशा में बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है."

सुखद बात यही है कि रेलवे के अधिकारी इन समस्याओं से अनभिज्ञ नहीं हैं. आंतरिक स्रोतों तथा जनता से अधिक धन उगाहा जा रहा है. रेलवे बांडों से लगभग 560 करोड़ रुपए इकट्ठे किए जा चुके हैं और इस वर्ष 500 करोड़ रुपए और प्राप्त होने की उम्मीद है. इस आय स्रोत से निश्चय ही बजट पर रेलवे की निर्भरता घट गई है. 1986-87 में जहां यह निर्भरता 50 प्रतिशत थी, इस वर्ष घटकर 22 प्रतिशत ही रह गई है.

यदि ऐसे ही रकम मिलती रहे तो पटरियों पर होने वाली क्रांति साकार हो सकेगी. लेकिन रेलों की गति सुधारने के अलावा यात्रियों की सुविधाओं के लिए और भी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है. तभी यह क्रांति सार्थक हो पाएगी.

—सुरजीत बासगुप्त

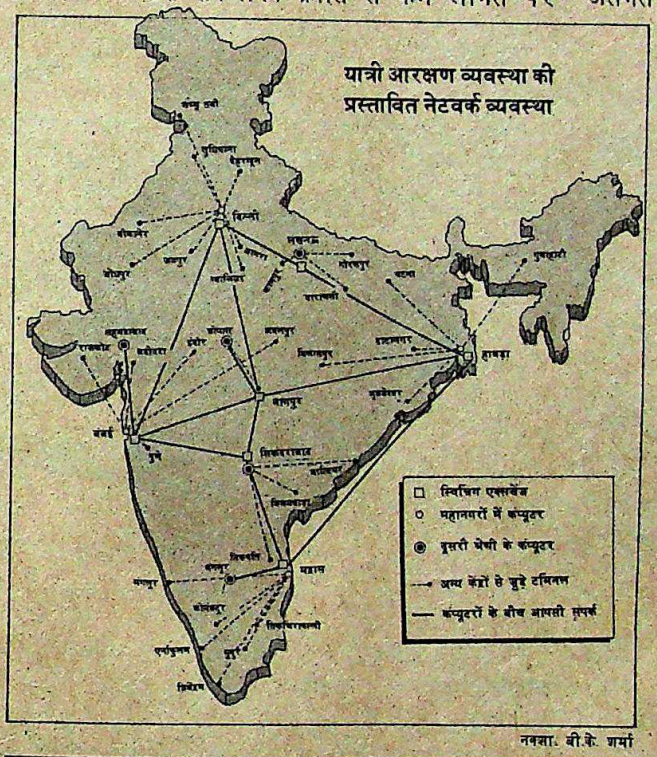

नक्शा: बी.के. शर्मा

"एक ही उपाय है वह यह कि तकनीकी सुधार करके मौजूदा पटरियों का ही और सही इस्तेमाल हो"

आर.के. जैन
अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विदेशी विमानसेवाएं

गिरते हुए शटर

एजेंटों की पौ-बारह

बड़े शहरों में विदेशी विमानसेवाओं के चमचमाते दफ्तर एक-एक करके बंद होते जा रहे हैं. इनकी बंदी की रफ्तार पहले धीमी थी, अब जोर पकड़ रही है.

केवल पिछले साल ही कम-से-कम आठ विदेशी विमान सेवाओं के दफ्तर बंद हुए या उन्होंने अपने कर्मचारियों को बंदी के नोटिस जारी कर दिए. एअर फ्रांस के विमान भारत से हर हफ्ते 14 उड़ानें भरते हैं. उसने पांच से ज्यादा शहरों से अपने दफ्तर उठा लिए हैं, जबकि ट्रांस वर्ल्ड एअरलाइंस (टीडब्लूए) ने भारत में अपने सभी दफ्तर बंद कर दिए हैं. गल्फ एअर ने भी दिल्ली व बंबई को छोड़ बाकी शहरों में ऐसा ही किया है. चार महीने पहले कुवैत एअरवेज ने दिल्ली का दफ्तर बंद कर दिया. सऊदी अरब की सबीना एअरलाइंस, केन्यन एअरवेज और इथियोपियन एअरवेज ने भी विभिन्न शहरों में शटर गिरा दिए.

दफ्तर बंद करने का अर्थ यह नहीं है कि ये विमानसेवा कंपनियां यहां से अपना कामकाज समेट रही हैं. दरअसल अपने कामकाज के लिए वे जनरल सेल्स एजेंट्स (जीएसए) नियुक्त कर रही हैं.

ये कंपनियां कहती हैं कि वे जीएसए इसलिए नियुक्त कर रही हैं ताकि कामकाज का खर्च घटाया जा सके. भारत में क्वांटाज के महाप्रबंधक मृणाल सेन दलील देते हैं, "हमारा कारोबार इस साल करीब 7 प्रतिशत बढ़ा जबकि उक्त खर्च 18 प्रतिशत बढ़ गया. इसकी मुख्य वजह थी— किरायों में 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं था." फिर भी क्वांटाज फिलहाल दफ्तर बंद करने की नहीं सोच रही. एअर फ्रांस के एक प्रवक्ता कहते हैं, "मद्रास दफ्तर के रखरखाव पर हमारी कंपनी सालाना 12 लाख रुपए का खर्च उठा रही है. अगर इसे बंद कर दिया जाए तो हम यह पैसा बचा सकते हैं."

इनमें से ज्यादातर कंपनियां अपनी कमाई का 20 प्रतिशत अपने दफ्तरों पर खर्च कर रही हैं. दफ्तर न होने पर जीएसए को मात्र 3 प्रतिशत अतिरिक्त कमीशन देना होता है (ट्रेवल एजेंटों को मिलने वाले अधिकतम 9 प्रतिशत के अलावा). इस तरह काफी बचत हो सकती है. जैसा कि गल्फ एअर के महाप्रबंधक (उत्तर) मुहम्मद राधी कहते हैं, "जीएसए का प्रयोग हमारे खर्च को करीब 40 प्रतिशत घटा देगा. यह जरूरी भी है क्योंकि शायद ही कोई विमानसेवा कंपनी भारत में मुनाफा कमा रही है."

लेकिन उनके इस किफायत अभियान का भारत की विदेशी मुद्रा आमदनी पर बुरा असर पड़ेगा क्योंकि उनके दफ्तरों के खर्चे बंद होने पर उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा विदेशी मुद्रा में उनको वापस चला जाएगा. एक उड्डयन विशेषज्ञ का विचार है कि करीब 5 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा का सालाना नुकसान हो सकता है.

नुकसान सरकारी खजाने को होगा. लेकिन इन विमानसेवाओं के अधिकारी दफ्तर बंदी के लिए सरकार को ही जिम्मेदार ठहराते हैं. सेन के मुताबिक, "ईंधन की ऊंची कीमतों, अनुचित सरकारी वसूलियों और विभिन्न टैक्सों के कारण विदेशी विमानसेवा कंपनियां भारत भर में अपने दफ्तर कम करने या उठा लेने पर मजबूर हो जाएंगी." उनकी बात में दम भी है. उदाहरण के लिए लैंडिंग फीस (हवाई अड्डा शुल्क) इस साल 10 प्रतिशत बढ़ा दी गई. और 'रूट नेवीगेशन चार्ज' में 20 प्रतिशत बढ़ोतरी की गई जबकि यहां ईंधन की कीमतें सिंगापुर व अमेरिका के मुकाबले दुगनी हैं. भारत उन गिने-चुने देशों में है जहां ईंधन की कीमतें सबसे ज्यादा हैं.

मगर दूसरी ओर इन कंपनियों के कर्मचारी कहते हैं कि उनकी कंपनियां भारत से बहुत ज्यादा कमाती हैं. बहुत से कर्मचारी दफ्तर बंदी के खिलाफ आवाज उठाने की तैयारी कर रहे हैं. करीब 200 लोगों को छंटनी के नोटिस दिए गए हैं जिनमें से कई अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं. हाल में एअर फ्रांस के छह कर्मचारियों को मद्रास में अपने दफ्तर की बंदी के खिलाफ स्थगन आदेश भी मिल गया.

बाजार में बेवजह तनाव है. मसलन जीएसए का जब 3 फीसदी कमीशन से काम नहीं चलता तो वे एजेंट के नौ फीसदी कमीशन में से हिस्सा बंटाने लगते हैं. दिल्ली का एक जीएसए कहता है, "यह बहुत ही गंदा काम है और कभी-कभी तो छूट 20 फीसदी तक जा सकती है क्योंकि आपको बाजार में बने रहना है."

लेकिन जीएसए की दूसरी एजेंसी के लोग इस आरोप को गलत बताते हैं. एअर ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्रीय बिक्री प्रबंधक (दक्षिण भारत) एस. शेषाद्री कहते हैं, "हम 3 फीसदी से भी काम चला सकते हैं क्योंकि माल की बुकिंग में अच्छी कमाई हो जाती है. जहां तक छूट की बात है, वह तो विदेशी विमानसेवा कंपनियां खुद ही तय कर देती हैं, हम छूट नहीं देते."

जीएसए को काम सौंपने पर बिक्री में वृद्धि हुई है. इटली की 'एलीतालिया' का दफ्तर जब मद्रास में था तो वहां से 15 फीसदी टिकट सीधे बिके. 1984 से नियुक्त उसका अब जीएसए उसके 40 फीसदी टिकट बेचता है. यानी जब तक जीएसए का धंधा चलता है और यात्री तथा विमानसेवा कंपनियां उनके माध्यम से पैसा बचाकर खुश हैं, तब तक ऐसी और कंपनियां भी अपने दफ्तर बंद कर सकती हैं.

—एस.एच. वेंकटरमनी और सुरजीत दासगुप्त

कार्टून: अजीत नाइनन

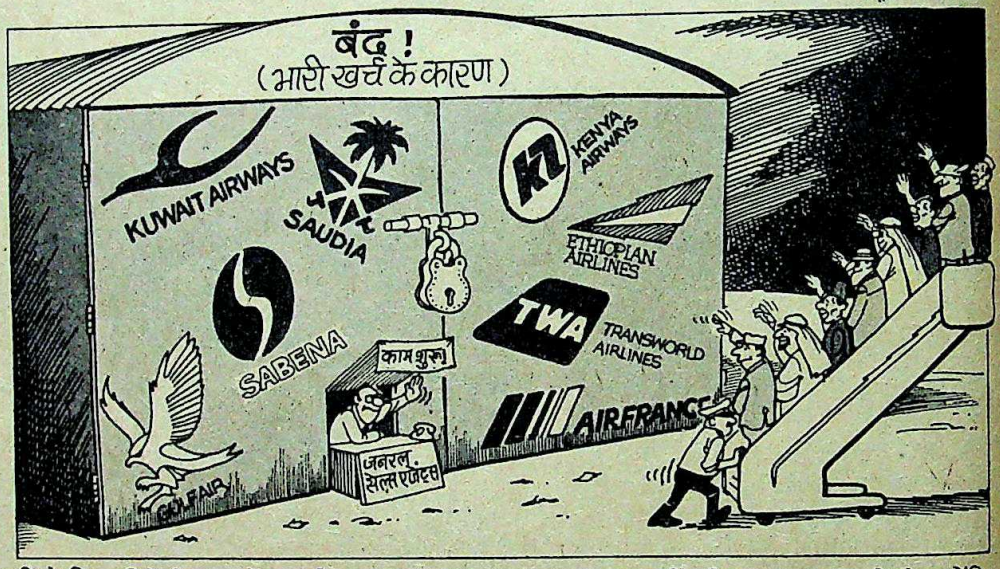

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रत्यक्ष कर विधेयक

बदलाव, या बदले का भाव

अफरातफरी में पारित विधेयक के प्रावधानों पर विवाद

यदि आप अग्रिम करदाता हैं तो 1989 के बाद से प्रतिवर्ष सितंबर के बाद अपना मकान अथवा मशीनरी नहीं बेच सकेंगे. ऐसा करने से जुर्माना लगेगा.

इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि यदि आपकी कंपनी प्रतिवर्ष पांच लाख रुपए का घाटा उठा रही है और टैक्स अधिकारी अपनी 'जांच' के दौरान पाते हैं कि घाटा वास्तव में तीन लाख रुपए का ही है तो वे इस अंतर—दो लाख रुपए— पर 30 प्रतिशत के हिसाब से जुर्माना ठोक देंगे. यानी सरकार लाभ ही नहीं, हानि पर भी टैक्स लगा सकती है.

इतना ही नहीं, कई अन्य बातों को भी अब कानून का रूप मिलने वाला है. पिछलें कई वर्षों में सबसे विवादास्पद इस विधेयक पर संसद की मंजूरी मिल चुकी है और अब यह राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए उनके पास पड़ा है. यह प्रत्यक्ष कर (संशोधन) विधेयक आयकर कानूनों में भारी फेरबदल करेगा. इन बदलावों में प्रमुख हैं :—

► सभी कंपनियों के लिए अप्रैल से मार्च तक एक ही वित्त वर्ष. अलग-अलग महीनों से हिसाब रखने वाली कंपनियों को भी 1989-90 में यही वित्त वर्ष लागू करना पड़ेगा. वैसे यह काम काफी उलझन भरा होगा.

► भागीदारी में चलने वाली फर्मों के लिए एक नई कर योजना. यह छोटी कंपनियों के साथ भेदभाव करेगी.

► 30 प्रतिशत अतिरिक्त कर जुर्माने का प्रावधान. आयकर अधिकारी करदाता द्वारा भरी गई रिटर्न तथा खुद के आकलन में अंतर होने पर 30 फीसदी जुर्माना लगा देंगे.

► वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों को नई इमारत आदि का अनुदान देने में दी जाने वाली राशि अब कर-मुक्त नहीं रहेगी.

► मालिकों को अपने कर्मचारियों तथा निदेशकों को दिए जाने वाले वेतन, सुविधाओं तथा बोनस पर कर नहीं देना पड़ेगा, अब तक यह छूट नहीं थी.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष एम.के. टिक्कू का कहना है, "बिल का उद्देश्य कर के नियमों को सरल करना, उन्हें अधिक प्रभावकारी बनाना तथा करों की चोरी को अधिक दंडनीय बनाना है." वे कहते हैं कि उनका विभाग करदाताओं के विश्वास पर ही काम करेगा. केवल पांच प्रतिशत संदेहास्पद करदाताओं के खातों की ही जांच करनी पड़ेगी.

लेकिन विधेयक की महत्वपूर्ण धाराएं उलझन में डाल देने वाली हैं. 'इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज़ ऑफ इंडिया' के अध्यक्ष बी.एस. दोरईस्वामी कहते हैं, "इरादे निस्संदेह नेक हैं लेकिन विधेयक के मुद्दों पर अधिक विस्तार से विचार-विमर्श किया जाना चाहिए था." पर यह किसी मुश्किल को बहुत हल्केपन से कहना ही है. 189 धाराओं वाला यह विधेयक संसद के दोनों सदनों से केवल चार घंटे की बहस के बाद ही पास कर दिया गया.

करों के विशेषज्ञ ननी पालखीवाला ने तो इसके विरोध में एक प्रमुख दैनिक में एक तीखा लेख भी लिखा. इंका सांसद और आठवें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के.पी. साल्वे ने भी सार्वजनिक रूप से इसका विरोध किया है. उद्योगपति और पूर्व जनता सांसद वीरेन जे. शाह का कहना है, "सत्र के अंतिम दिन तुरत-फुरत में ऐसे विधेयक को पास करना लोकतांत्रिक मान्यताओं पर तीखा प्रहार ही है."

अधिकारियों का कहना है कि इस विधेयक पर अधिक बहस निरर्थक थी, क्योंकि यह विधेयक अगस्त 1986 में संसद में पेश श्वेतपत्र पर आधारित था. वित्तमंत्री नारायण दत्त तिवारी भी यही मानते हैं कि पिछले दो वर्षों में इस विषय पर व्यापक बहस हो चुकी है. वे कहते हैं, "बहस का पर्चा सदन में बांटा गया था. सांसदों की परामर्शदात्री समिति की बैठकों में इस पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया था."

प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि साल्वे चार सांसदों के उस दल में सम्मिलित थे जिसने इस विधेयक को अंतिम रूप दिया है. लेकिन साल्वे, जो पहले इस्पातमंत्री रह चुके हैं, सरकार पर विश्वासघात करने का आरोप लगाते हैं. वे कहते हैं, "जिन मुद्दों पर सहमति हुई थी, विधेयक उनके अनुरूप नहीं है. अब हम खुद को अपराधी महसूस करते हैं."

कर संशोधनों को संचार माध्यमों से प्रचारित करने का सरकारी दावा निस्संदेह सही है लेकिन यह भी सही है कि कानूनी दस्तावेज तथा उस पर टिप्पणी में काफी अंतर रहता है. जैसा कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एस.के. दासगुप्त का कहना है, "जो पर्चा पढ़ा गया उसमें सिद्धांतों पर तो चर्चा की

कार्टून: अजीत नाइनन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गई लेकिन कर संबंधी ब्यौरे नहीं दिए गए."

पिछले पखवाड़े कई कर विशेषज्ञों ने जब इस संशोधन की धाराओं को देखा, तो वे भौंचक रह गए. सरकारी आश्वासन के उलट यह विधेयक आयकर अधिकारियों के निरंकुश अधिकारों पर कोई रोक नहीं लगाता. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष येज़दी ए. मालगम का मानना है, "इस विधेयक में ऐसी अनेक व्यवस्थाएं हैं जिनसे आयकर अधिकारी के सहमत होने पर ही खर्च में कटौती मान्य होगी. यह पूरी तरह से उनकी मर्जी पर आधारित है." उदाहरण के लिए 30 प्रतिशत अतिरिक्त कर को ही लें. इस मामले में आयकर अधिकारी बड़े आसानी से कह सकता है कि आपने अपनी आय जितनी बताई है वह उससे अधिक है. इसलिए उस पर अतिरिक्त कर देना पड़ेगा.

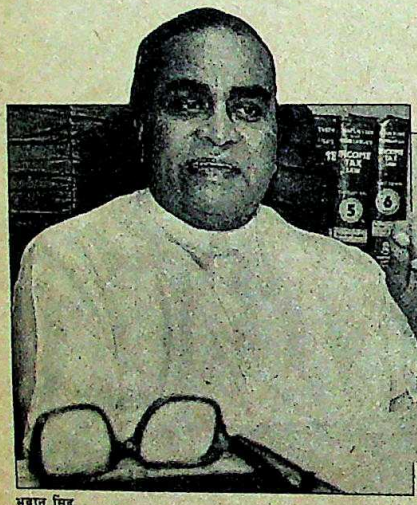

भवान सिंह

'फिक्की' के पूर्व अध्यक्ष तथा उद्योगपति डी.सी. कोठारी भी मानते हैं कि सुविधाओं पर कर में छूट चाहने वाले नौकरीपेशा लोगों को इससे कठिनाई आएगी. अगर कर अधिकारी छूट नामंजूर कर देते हैं तो उन पर जुर्माना थोपा जा सकता है. साफ है कि जुर्माने संबंधी धारा और ज्यादा कठोर हो सकती है, खासकर तब जबकि अग्रिम कर में पूंजीगत लाभ भी जोड़ दिए जाएं. लेकिन वीरेन शाह का कहना है, "आय के निर्धारण में भूल का जुर्माना बहुत ज्यादा है. इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा. कोई भी आयकर अधिकारी आपको परेशानी से बचाने के लिए पैसा मांग सकता है."

समान वित्त वर्ष का प्रावधान इसलिए है ताकि कंपनियों के सालाना बही-खातों की तुलना आसानी से करके कर की व्यापक गड़बड़ियां दूर की जा सके. लेकिन इसके लिए पहले कई दूसरे कानूनों में संशोधन

"इरादे निस्संदेह नेक हैं. लेकिन इस विधेयक के सभी मुद्दों पर अधिक विस्तार से विचार किया जाना चाहिए था"

बी.एस. दोरईस्वामी
अध्यक्ष, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया

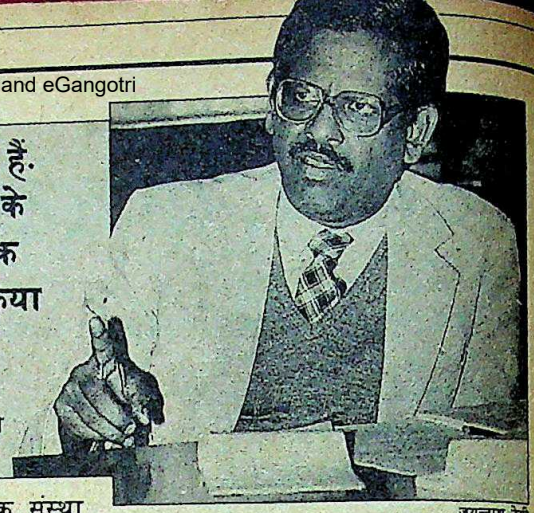

जगन्नाथ नेगी

जरूरी है. लेखा परीक्षकों की एक संस्था 'प्राइस वाटरहाउस' के भागीदार अमल गांगुली कहते हैं, "कंपनियां जब तक अंतरिम लाभांश की घोषणा नहीं करेंगी, ढेर सारे शेयर होल्डरों को उनका लाभांश नहीं मिल सकेगा." इसके साथ ही कंपनियों को हर साल अपने कारोबार का सालाना विवरण एक साथ छापना होगा. फिर एक साथ छापाखानों, और वार्षिक बैठकें आयोजित करने के लिए हॉलों की बुकिंग के लिए हंगामा मचेगा. उन्हें इन सब झमेलों के

"जिन मुद्दों पर सहमति हुई थी, विधेयक उनके अनुरूप नहीं है. अब हम खुद को अपराधी महसूस करते हैं"

एन.के.पी. साल्वे
अध्यक्ष, योजना आयोग

साथ काम करना सीखना होगा. जैसा कि कर विशेषज्ञ एच.पी. रनीना कहते हैं, "शुरू में तो कुछ मुश्किलें जरूर होंगी पर ऐसी नहीं कि दूर न की जा सकें."

दरअसल साझेदारी वाली कंपनियों के लिए नए प्रावधानों के कारण ज्यादा आशंकाएं उठ रही हैं. अब साझेदारी कंपनियों को अलग मानकर अधिकतम कर की दर 50 फीसदी कर दी गई है जबकि वर्तमान दर 22 से 24 फीसदी हीं है. लेकिन साझेदारों की आय पर कर नहीं लगेगा. अगर कंपनी पर लगने वाले कर तथा प्रत्येक साझेदार पर लगने वाला कर जोड़ दिया जाए तो बड़ी कंपनियों के साझेदारों को 50 प्रतिशत तक टैक्स देना पड़ जाएगा. इसलिए नए कानून से बड़ी कंपनियों को फायदा होगा. लेकिन यह कानून छोटी साझेदारी वाली कंपनियों के साथ अन्याय करता है, क्योंकि उनका वर्तमान कर 50 प्रतिशत से काफी कम है. लेकिन अब यह एकाएक बढ़ जाएगा.

इन सबका उद्देश्य कर चोरी रोकना है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के एक नोट के अनुसार कई साझेदारों वाली कंपनियां सिर्फ इसीलिए बनती हैं ताकि कम दर से कर देना पड़े और करों में छूट भी मिल जाए लेकिन अब कर की दर बढ़ा देने के बाद यह नहीं हो सकेगा.

लेकिन असल में जो बात खटकती है वह है गलतियों के बारे में इसमें किया गया पूर्वानुमान. वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी निजी बातचीत में कहते हैं, "इस विधेयक के पीछे मान्यता यह है कि हर आदमी धोखेबाज है." लेकिन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष इस धारणा का विरोध करते हैं उनका मानना है कि करदाता पर भरोसा रखना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी अंकुश कायम रखना भी है. वित्तमंत्री नारायणदत्त तिवारी ने कहा, "समान वित्त वर्ष की व्यवस्था और 30 प्रतिशत कर के जरिये ही अंकुश रखा गया है. इससे दुबारा कर निर्धारण आसान हो जाएगा." उन्होंने यह भी कहा कि इस विधेयक की गड़बड़ियां सुधारी जा सकती हैं.

इस मान्यता पर कुछ ही लोगों का यकीन है कि कर सीमा उठा लेने के साथ ही वेतन अपनेआप काफी बढ़ जाएगा. मालगम कहते हैं कि कर्मचारियों के वेतन कंपनी कानून में निर्धारित प्रबंधकीय पारिश्रमिक सीमाओं से निर्धारित होते हैं. उनकी इस मान्यता का समर्थन कम-से-कम एक कंपनी के प्रमुख ने किया. जीईसी समूह के अध्यक्ष ए.के. खोसला कहते हैं कि उनका समूह वेतन के अपने अंतर्संबंधों को कायम रखना चाहता है. ये वेतन निदेशक को दिए जाने इसका अच्छा पहलू एक ही हो सकता है कि इन करों के डर से गुपचुप होने वाले भुगतान काफी हद तक कम हो जाएंगे.

लेकिन अगर इतनी भी उपलब्धि इस विधेयक से मिल जाए तब भी कहा जा सकेगा कि कुछ तो हासिल हुआ.

—पलकुन्नथु जी. मथाई और सलिल त्रिपाठी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मैं बेहद... सुदृढ़ हूँ

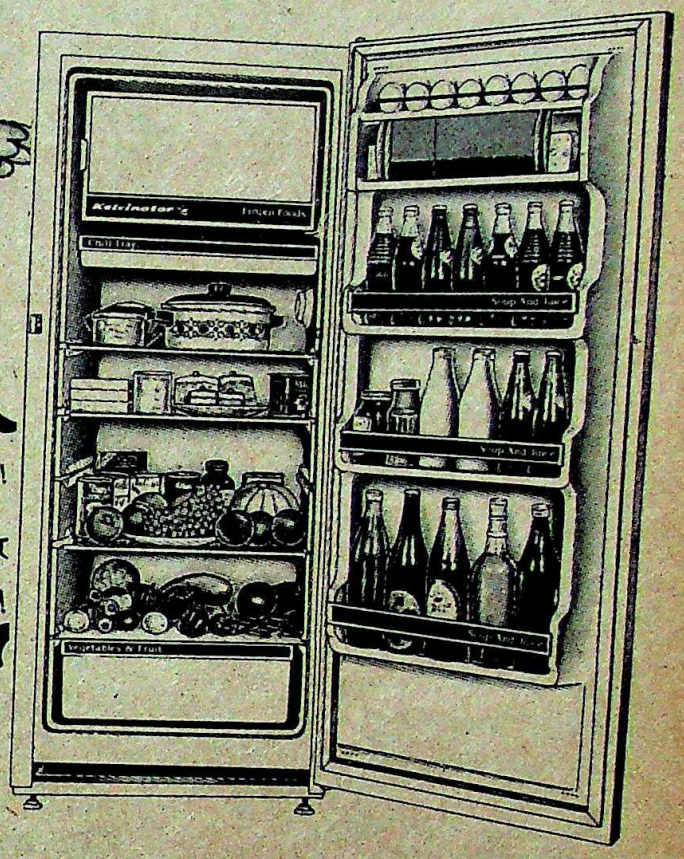

(सम्राट पेंगविन के एक के ऊपर एक पंख, उसके सौन्दर्य में ही चार चांद नहीं लगाते, बल्कि उत्तम इन्सूलेशन भी प्रदान करते हैं। तथा दो महीने की अण्ड-सेवन अवधि के दौरान प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों में भी उसे जीवित रखने में सहायता देते हैं जब तापमान गिर कर हो जाता है — 40° से 60° सें. के बीच!!
सुदृढ़, है न!!)

सन्दर्भ : रीडर्स डाईजेस्ट की एन्साक्लिका एण्ड बर्ड्स आफ़ दि वर्ल्ड, लेखक ऑलिवर एल. ऑस्टिन जूनियर प्रकाशक : ऑटीमम

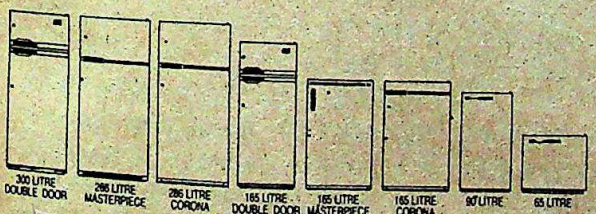

केल्विनेटर
रेफ्रिजरेटर
"इसकी ठण्डक...बेमिसाल!"

केल्विनेटर रेफ्रिजरेटर. सुदृढ़ बनावट।

इसका अत्यंत मज़बूत हृदय है — विश्व विख्यात 'पावर-सेवर' कम्प्रैसर। सब से सुदृढ़ जिसके खराब होने की सम्भावना न के बराबर। यह व्यापक उच्च तापमान में भी उतनी ही तेज़ी से ठंडा करता है। वोल्टेज के विस्तृत उतार चढ़ाव सहन करता है। तथा बिजली की खपत न्यूनतम करता है।

मज़बूत ए बी एस लाइनर। आधुनिक एवं उत्तम। जिसमें ज़ंग, पपड़ी लगने या खाने की सुगंध रचने का डर नहीं।

स्टील की मज़बूत सुदृढ़ बॉडी। इपाक्सी फ़िनिश, घिसाव एवं पपड़ी रोकता है।

और सोने पर सुहागा यह कि केल्विनेटर रेफ्रिजरेटर अनुपम बाहरी फिनिश तथा मनभावन अन्दरूनी रंगों में उपलब्ध है। जिन के कारण इनकी सुन्दरता देखते ही बनती है!

विशेष खूबियाँ :

* पूर्ण इन्सूलेशन कैबिनेट तापमान को बेहतर बनाती है।
* सर्विस में विश्वसनीय।
* बिजली की खपत में अत्यंत किफ़ायती।
* विशाल स्टोरेज क्षमता।
* अनेक मॉडल।

बिक्री एवं सर्विस के लिए :
एक्सप्रो मशीनरी लिमिटेड
प्रगति टावर, 26 राजिन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली-110 008.

286 लिटर तथा 165 लिटर मॉडल, डी जी एस एण्ड डी रेट कान्ट्रैक्ट पर भी उपलब्ध

Mutual-4510A HN

केल्विनेटर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रचारक ग्रंथावली योजना

चमत्कारी प्रयास

भ्रष्टाचार का नासूर उजागर

कुछ समय पूर्व वाराणसी के हिंदी प्रचारक संस्थान ने घोषणा की थी कि वे भारतेंदु हरिश्चंद्र, देवकीनंदन खत्री और बंकिमचद्र चटर्जी की सभी रचनाओं वाली तीन ग्रंथावलियों का पूरा सेट एक सौ रुपए में प्रकाशित करने जा रहे हैं. तब हिंदी प्रकाशन, वितरण और बिक्री से जुड़े लोगों ने इसे 'चंडूखाने' की खबर मानते हुए इसे हंसी में उड़ा दिया था. लेकिन पिछले दिनों संस्थान ने इस शृंखला की पहली कड़ी 'भारतेंदु समग्र' जारी करके न केवल इन लोगों को चौंका दिया बल्कि हिंदी प्रकाशन उद्योग में पनपने वाले भ्रष्टाचार के नासूर को भी जगजाहिर कर डाला.

1150 पृष्ठों की साहित्यिक सामग्री, 16 पृष्ठों में दुर्लभ चित्रों, पक्की जिल्द, बढ़िया कागज़, फोटोटाइप सेटिंग और खूबसूरत ऑफसेट छपाई वाली इस ग्रंथावली की कीमत 30 रुपए रखी गई है. एक और प्रकाशक द्वारा भारतेंदु साहित्य पर आधारित 'भारतेंदु— प्रतिनिधि रचनाएं' की कीमत (150 रु.) को देखते हुए तो संस्थान की यह ग्रंथावली लगभग मुफ्त दिखाई देती है. वर्तमान बाजार दरों के हिसाब से इस ग्रंथावली की कीमत उपरोक्त पुस्तक पर दुकानदार को मिलने वाले कमीशन (लगभग 40 फीसदी की चालू दर से 60 रु.) से भी आधी बैठती है जबकि 'भारतेंदु समग्र' का आकार इसके आकार (364 पृष्ठ) से लगभग चार गुना है. सिर्फ इतना ही नहीं, एक खास संख्या में बिक्री होने के बाद संस्थान को हर प्रति पर 6 रु. मुनाफा होने की उम्मीद है. ग्रंथावली की खूबी यह है कि इसमें भारतेंदु द्वारा रचित पूरा साहित्य, उनके पत्र और यहां तक कि उनके लिखे विज्ञापन भी बिना कांट-छांट के, ज्यों के त्यों छापे गए हैं.

कुछ दिनों के भीतर ही खत्री और बंकिम के संपूर्ण साहित्य वाली दोनों ग्रंथावलियां भी बाजार में आ जाएंगी. इनकी कीमत क्रमशः 40 और 30 रु. रखी गई है. 34 साल से पुस्तक आंदोलन से जुड़े और संस्थान के निदेशक कृष्णचंद्र बेरी कहते हैं, "इतने थोड़े दाम में अच्छे स्तर का ग्रंथ पाठक के हाथों में देकर हम उसे इस बात का भान करा सकेंगे कि बाजार में किताबों की ऊंची कीमतें महंगाई की वजह से नहीं बल्कि प्रकाशन व्यवसाय में घुसे कमीशनखोरों, बिचौलियों और अंधाधुंध मुनाफा कमाने आए लोगों के कारण हैं."

ग्रंथावली योजना के अर्थशास्त्र का खुलासा करते हुए वे बताते हैं, "15 हज़ार प्रतियां बेचने पर मामला बराबरी पर छूटेगा. मांग 25 हजार से ऊपर रही तो हमारा मुनाफा 20 प्रतिशत होगा." ग्रंथावली की बिक्री में से दुकानदारों और बिचौलियों का पत्ता पहले दिन से ही साफ कर दिया गया. लाइब्रेरियों को भी अग्रिम भुगतान के साथ अपना आर्डर भेजना होगा.

लेकिन एक ऐसे बाजार में जहां कागज़, छपाई और बाइंडिंग के दाम आसमान छू रहे हों क्या वहां पुस्तकों के दाम कम रखे जाने संभव हैं? इस बारे में राजपाल ऐंड संस के निदेशक ईश्वरचंद्र खंडेलवाल बताते हैं, "कुछ साल पहले तक किताब की कीमत उस पर आने वाली लागत की ढाई गुना रखी जाती थी. अब यह अनुपात चार गुना है. लेकिन ऐसे प्रकाशक भी हैं जो असली लागत से दस गुना ज्यादा कीमत किताबों पर छाप रहे हैं." हिंदी बुक सेंटर के प्रबंध निदेशक अमरनाथ का कहना है, "आजकल किताबें पाठक के लिए नहीं बल्कि कुछ खास किस्म के गिने-चुने खरीदारों के लिए छापी जा रही हैं." बाजार में नजर दौड़ाने से पता चलता है कि भारत में आज हिंदी पुस्तकों के खरीदारों की सूची में आम पाठक का स्थान बहुत नीचे है. इन प्रकाशनों के खरीदार या तो पुस्तकालय हैं या सरकारी और अर्ध-सरकारी विभाग. अपवादों को छोड़कर इनमें से लगभग सभी जगह किताब खरीदने का पैमाना मेज के नीचे मिलने वाला कमीशन होता है.

बांग्ला में अच्छा साहित्य सस्ते दामों में मिल सकता है तो क्या कागज और छपाई सिर्फ हिंदी के लिए ही महंगी है?

—कृष्णचंद्र बेरी
निदेशक, हिंदी प्रचारक संस्थान

अमरनाथ कहते हैं, "ऐसे में आप 10 क्या 20 गुना भी कीमत छाप दें तो किसी को क्या एतराज होगा? पर इस परंपरा ने किताबें बेचने के मामले में प्रकाशक और विक्रेता के बीच भी एक होड़ शुरू कर दी है." बिक्री के सिकुड़ते दायरे की ओर ध्यान खींचते हुए खंडेलवाल बताते हैं कि उनके यहां पहले किसी भी पुस्तक के पहले संस्करण की लगभग 5 हजार प्रतियां छापी जाती थीं. आजकल यह औसत केवल 12-13 सौ तक रह गया है. हालत तब और भी हास्यास्पद लगती है जब ऐसी बातें सुनने को मिलें कि गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की रचनाओं के पहले रूसी संस्करण की पौने सात लाख प्रतियां बिकीं.

'भारतेंदु समग्र' के युवा संपादक और संस्थान के निकट सहयोगी हेमंत शर्मा (28) ग्रंथावली के कम दामों का औचित्य सिद्ध करते हुए कहते हैं, "अगर बिचौलियों को कमीशन देने के बजाय यह पैसा आप पाठक की जेब में डाल दें तो किताब सस्ती भी होगी और लोकप्रिय भी." बांग्ला में इस तरह के प्रकाशनों की परंपरा काफी सफल रही है. शरत शती के अवसर पर उनके पूरे साहित्य की ग्रंथावली 100 रु. में प्रकाशित की गई जो इतनी लोकप्रिय हुई कि उसका दाम घटाकर 90 रु. कर दिया गया. इसी तरह पूर्ण रवींद्र साहित्य के 17 खंड 600 रु. में प्रकाशित किए गए. बेरी पूछते हैं, "अगर बांग्ला में अच्छा साहित्य सस्ते दामों में मिल सकता है तो क्या कागज़ और छपाई हिंदी के लिए ही महंगी हैं?"

'भारतेंदु समग्र' की सज्जा व छपाई की क्वालिटी और संपादन सभी में संपादक की मेहनत और रुचि की झलक मिलती है. विशेष रूप से ग्रंथावली के आरंभ में हेमंत शर्मा द्वारा लिखा गया 23 पृष्ठों का संपादकीय 'भारतेंदु को पढ़ने के बाद' बहुत सरल शब्दों और सहज शैली में भारतेंदु का अंतरंग परिचय देता है.

कुल मिलाकर यह ग्रंथावली हिंदी प्रकाशन के शुभचिंतकों का ध्यान इस बात की ओर खींचने के लिए काफी होनी चाहिए कि जब तक कमीशनखोरी, अस्वस्थ व्यापारिक होड़ और सरकारी खरीद पर अति निर्भरता के दीमक से यह अपने आपको मुक्त नहीं करता, तब तक न तो उसकी अपनी हालत सम्मानयोग्य होने वाली है और न हिंदी पाठक के मन में किताबों के प्रति आकर्षण जगाया जा सकता है. —विजय क्रांति

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

निर्यात

संभावनाएं असीम

उदार नीतियों से हौसला बढ़ा

निर्यातकों की पौ-बारह होने लगी है, खासकर उन निर्यातकों की किस्मत खुल गई है जिनका कारोबार पहले ठीक नहीं चल रहा था. विदेशी बाजारों में कई बरस जूझने के बाद निर्यातक अब बिक्री और मुनाफे के मामले में आगे बढ़ रहे हैं. रुपए के अवमूल्यन का भी इसमें बड़ा योग है. इससे विदेशी खरीदार को भारतीय माल सस्ता पड़ने लगा है और निर्यातक भी अपने उत्पाद की अच्छी कीमत पाने लगा है. इसके अलावा सरकार की उदार आर्थिक नीतियों के चलते भी निर्यातकों की हिम्मत बंध गई है.

और यह बात निर्यात में बढ़ोतरी से स्पष्ट भी होती है. सरकारी आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल-अक्तूबर 1987 में निर्यात में 27.2 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. एक सरकारी एजेंसी की भविष्यवाणी है कि पूरे साल में निर्यात में बढ़ोतरी 15 फीसदी रहेगी.

वैसे अभी भी निर्यात के मामले में देश सबसे अधिक चमड़े या उससे बने सामान और सिले वस्त्रों पर ही निर्भर है (चार्ट देखें). अब वाणिज्य मंत्रालय इस पर भी ध्यान दे रहा है और पिछले पखवाड़े वह निर्यात की जाने वाली चीजों की सूची बढ़ाने की रणनीति तैयार कर रहा था. उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में ही तीन साल के लिए नरम आयात-निर्यात नीति घोषित की जाए. दूसरी चीजों के अलावा इसमें इंजीनियरिंग और निर्माण संबंधी निर्यात बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा.

इसी बीच व्यापार संबंधी नवीनतम आंकड़ों से कुछ बड़े सवाल उठ खड़े हुए हैं. रकम के हिसाब से तो निर्यात बढ़ा है. पर क्या अधिक माल भी भेजा जा रहा है? या यह सिर्फ कीमत बढ़ने से हुआ है? वाणिज्य राज्यमंत्री प्रियरंजन दासमुंशी का कहना है कि यह बढ़ोतरी हवाई नहीं है.

पर उनकी बात से अनेक निर्यातक सहमत नहीं. चमड़ा निर्यात परिषद के अध्यक्ष एस.एम. हाशिम कहते हैं कि चमड़े के निर्यात में वृद्धि का 20 फीसदी श्रेय तो मुद्रा के अवमूल्यन और कीमतों में वृद्धि को जाता है. और 80 फीसदी श्रेय चमड़े के तैयार माल को जाता है जिनका बाहर जाना बढ़ गया है. मद्रास स्थित कुणाल समूह की कंपनियों के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक दीपक बनकर भी उनकी बात से सहमति जाहिर करते हैं.

बड़ी कंपनियां भी निर्यात बढ़ने की बात करती हैं. साबुन और डिटर्जेंट बनाने वाली हिंदुस्तान लीवर को उम्मीद है कि 1987-88 में उसके निर्यात में 20 फीसदी वृद्धि होगी. टाटा एक्सपोर्ट्स का कारोबार इस साल कम हुआ है. पर इसके निदेशक एच.एच. मलघम कहते हैं, "जिन चीजों पर कर्ज मिलने में मुश्किल होती है, उनका निर्यात हमने बंद कर दिया है. इसी वजह से हमारा निर्यात गिरा है." पोंड्स इंडिया के कार्यकारी उपाध्यक्ष वी. बलरामन कहते हैं, "हम पिछले साल के मुकाबले इस साल अधिक निर्यात कर रहे हैं."

हां, एक चीज एकदम साफ है कि ढेर सारी मुश्किलों के बावजूद निर्यात बढ़ा है, हालांकि हो सकता है कि सरकारी आंकड़े बहुत ठीक न भी हों. मेट्रो एक्सपोर्ट्स के अध्यक्ष चंदूभाई उदेशी की शिकायत है, "निर्यातकों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है." 20 करोड़ रुपए सालाना कारोबार वाली कंपनी झालानी टूल्स (पूर्व नाम गेडोर टूल्स) के संयुक्त निदेशक अनूप झालानी कहते हैं कि उन्हें बिजली की कमी, अधिक दर पर कर्ज, बंबई के परिवहन वालों की हड़ताल का सामना करना पड़ता है. साथ ही लागत खर्च भी बढ़ता जा रहा है जबकि उनके ताइवानी प्रतिद्वंद्वियों का ऐसी मुश्किलों से साबका नहीं पड़ता.

इसके बावजूद सरकारी नीति से निर्यात को बढ़ावा मिला है. (नीति के अनुसार निर्यातक अपने व्यापार के लिए निर्यात से होने वाला आधा मुनाफा रख सकते हैं). साथ ही विदेशी मशीनों और कच्चे माल को मंगाना भी आसान हो गया है. सरकार ने विशेष ध्यान देने के लिए 14 क्षेत्रों को चुना है. लेकिन व्यवहार में चमड़ा, जवाहरात, गहनों और कपड़ों के निर्यात को ही खास प्रोत्साहन दिया गया है.

चार्ट बी.के. शर्मा

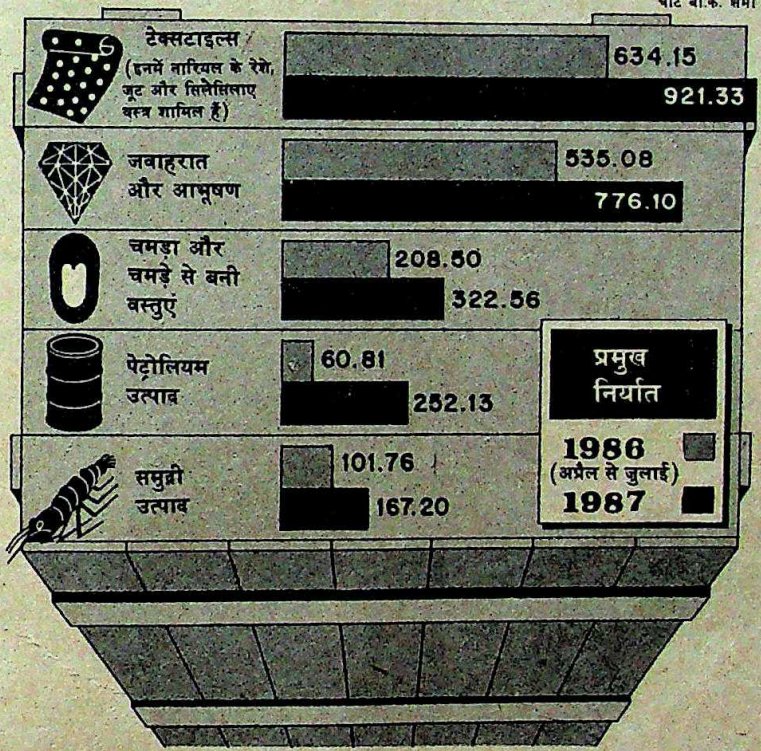

अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है: क्या यह उफान बना रह सकेगा? आज पश्चिमी देश जिस तरह से अपने दरवाजे बंद करते जा रहे हैं, उससे मुश्किलें पैदा हो सकती हैं, खासतौर से कपड़ों के निर्यात के लिए. दूसरे, रुपया एक सीमा से नीचे नहीं जा सकता क्योंकि इससे आयात की कीमत हासिल नहीं की जा सकेगी. एक वरिष्ठ सरकारी अर्थशास्त्री इतना तक तो मानते हैं पर उनका कहना है कि अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत हो रही है सो निर्यात भी तो बढ़ेगा. वे कहते हैं, "हमारी स्थिति दुनिया की प्रतिद्वंद्विता में टिकने वाले की बनती जा रही है."

यह शायद कुछ ज्यादा ही बड़ा दावा है. पर जवाहरात और गहना निर्यात संवर्द्धन परिषद के अध्यक्ष जतिन मेहता भी इसी तरह की बात करते हैं. वे कहते हैं, "दुनिया का बाजार काफी बड़ा है. और भारत के हर गांव में सुनार हैं." इंजीनियरिंग उद्योग संघ के महानिदेशक तरुण दास भी इंजीनियरिंग सामान के निर्यात में धीरे-धीरे वृद्धि की भविष्यवाणी करते हैं.

अगर आगे का काम इन्हीं भविष्यवाणियों के अनुरूप ही हो पाया तो निर्यात के मामले में तूफान आने ही वाला है.

—पलकुन्नथु जी. मथाई और सलिल त्रिपाठी, सुरजीत बासगुप्त के साथ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शेयर बाजार

दुलकी चाल

उफान के कुछ लक्षण जाहिर

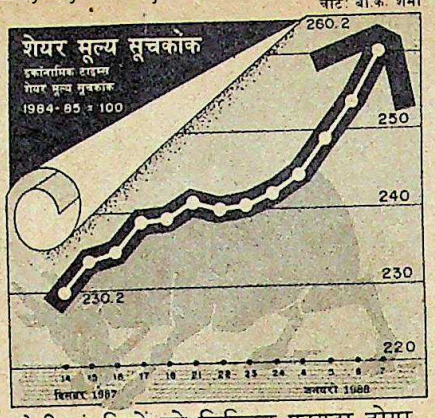

यह पखवाड़ा उदासीनता और उम्मीदों का था. 1987 के आखिरी हफ्ते में शेयर बाजार (कलकत्ता को छोड़कर) छुट्टियां मना रहे थे सो नए साल के शुरू तक भी छुट्टियों का असर रहा.

इसके बावजूद उत्साह वाला रुख छाया रहा. शेयर बाजार के अधिकांश लोगों का मानना है कि सरकार सुस्त पड़ते शेयर बाजार में जान फूंकने के लिए गंभीर है. कुछ ही हफ्तों बाद आने वाले बजट में वह निवेशकों के फायदे के लिए कुछ करेगी.

हाल में इस्पात, खाने के तेलों और चीनी के दाम बढ़ाने से इस बात के संकेत मिलते हैं. इस्पात की कीमतें बढ़ाने का एक असर तो यह होगा कि टिस्को की झोली में 110 करोड़ रुपए अधिक पहुंच जाएंगे. इसी तरह अगर सरकार सिंथेटिक धागों पर करों की रियायत देती है तो रिलायंस और जे.के. जैसी कंपनियों को निश्चित फायदा होगा.

उम्मीद है कि अगले कुछ ही हफ्तों में घोषित होने वाली आयात-निर्यात नीति में सरकार उद्योगों के लिए कुछ लाभदायक घोषणाएं करेगी. हो सकता है कि इंजीनियरिंग उद्योग के सामान और चाय के निर्यात को ज्यादा फायदे का बनाया जाए या फिर इनके लिए नवीनतम मशीनें मंगाने की अधिक सुविधा दी जाए. हाल में आयात पर लगी कुछ पाबंदियों को भी शायद समाप्त कर दिया जाए. सरकारी कमेटी ने भी ऐसा ही सुझाव दिया है.

वैसे भी शेयर बाजार उम्मीदों के सहारे ही फलता-फूलता है और यही कारण है कि शेयरों की कीमत में सामान्य उछाल आया है. बास्फ, हिंदुस्तान एलॉयज़, सी.पी. टूल्स, क्लोकनर विंडसर जैसे शेयर चढ़े हैं. इनमें कुछ तो साल भर से सुस्त चल रहे थे. इससे पता चलता है कि शेयर बाजार शायद मंदी के दुष्चक्र से निकल रहा है.

इस बात के भी संकेत हैं कि तेजड़िए बाजार में सक्रिय हो चुके हैं. अनेक शेयर काफी चढ़े हैं. पिछले पखवाड़े बजाज ऑटो 500 रुपए, सेंचुरी एंका 142 रुपए, फिनोलेक्स केबल्स 75 रुपए और टिस्को के शेयर 70 रुपए चढ़ गए.

वैसे ध्यान देने लायक बात यह है कि रिजर्व बैंक द्वारा आर्थिक स्थिति खराब होने की भविष्यवाणी के बावजूद ऐसा हुआ है. नारायणदत्त तिवारी ने कुछ समय पहले कहा था कि सरकार शेयर बाजार की स्थिति ठीक करने के लिए जरूरी कदम उठाएगी. शायद यह इसी का असर है.

इसके बावजूद आने वाले वर्ष में थोड़ी सावधानी रखनी होगी. आगे सूखे का असर कंपनियों की बैलेंस शीट पर भी दिखाई पड़ने लगेगा. इसके बावजूद बजट तक का समय तो उत्साहजनक लगता है और इस दौरान अनेक शेयर ऊपर चढ़ सकते हैं.

जमा स्टॉक

	1988 ऊंचा	1988 नीचा	बंद 7.1.88	पखवाड़े में स्थिति
अशोक लेलैंड	47.25	28.00	35.50	4.00 +
एसोसिएटेड सीमेंट	241.50	129.00	160.00	9.00 +
एटलस कोप्को	152.00	46.00	54.00	4.00 +
एशियन पेन्ट्स	272.50	132.50	161.25	18.75 +
बजाज ऑटो	5860.00	3950.00	4850.00	500.00 +
बड़ौदा रेयॉन	270.00	137.50	160.00	15.00 +
बाटा इंडिया	160.00	59.50	69.00	7.75 +
बेयर	785.00	300.00	320.00	—
भारत फोर्ज	140.00	63.00	116.00	17.00 +
बिरला जूट	58.00	35.75	43.20	3.95 +
ब्लो प्लास्ट	178.00	92.50	125.00	9.00 +
बॉम्बे डाइंग	143.00	40.50	110.50	18.75 +
ब्रिटानिया इंडिया	190.00	85.00	102.00	7.00 +
बुक बांड	109.00	75.50	85.00	5.00 +
सीएट टायर्स	86.00	45.00	84.50	5.50 +
सेंचुरी एंका	1175.00	815.00	1182.00	142.00 +
क्लोराइड इंडिया	148.00	67.00	78.00	—
सितुरगिया	77.50	53.00	70.00	8.00 +
कोलगेट	415.00	182.50	209.00	16.00 +
डीसीएम	47.00	20.00	37.50	9.50 +
डनलप	101.50	71.25	79.00	3.00 +
एस्कार्ट्स	84.00	35.00	41.50	2.75 +
फिनोलेक्स केबिल्स	380.00	114.00	365.00	75.00 +
फूड स्पेशिलिटीज	188.50	119.00	135.00	5.00 +
गोदरेज नाइलोन	36.00	17.50	21.00	0.50 +
जी.ई. शिपिंग	35.50	16.00	20.85	3.90 —
गुजरात स्टेट फर्टि.	183.50	74.00	103.50	16.50 +
ग्रासिम इंडिया	118.00	80.00	103.00	7.00 +
हिंडु. एल्यूमिनियम	143.00	71.00	124.00	13.00 +
हिंदुस्तान कोकोआ	262.50	156.25	205.00	15.00 +
हिंदुस्तान लीवर	212.00	64.00	77.00	7.00 +
हिंदुस्तान मोटर्स	35.35	16.70	24.20	1.70 +
हिंदुस्तान डॉर	407.50	140.00	205.00	30.00 +
आई.ई.एल	64.75	36.00	41.50	1.00 +
भारतीय होटल	130.00	62.50	105.00	2.50 +
इंडियन आर्गेनिक	78.00	20.00	22.00	2.00 —
इंडियन रेयॉन	76.50	48.00	55.00	3.00 +
इंद्राल	510.00	160.00	223.75	41.25 +
इंगरसॉल-रैंड	360.00	265.00	332.50	37.50 +
आई.टी.सी.	78.00	37.50	38.50	—
जे.के. सिंथेटिक्स	93.50	39.50	66.50	8.00 +
काइनेटिक इंजी.	312.50	137.50	176.25	3.75 —
किर्लोस्कर क्युमिस	97.50	40.00	54.00	2.00 +
केएसबी पम्प	480.00	220.00	398.75	18.75 +
लारसन-टुब्रो	107.00	67.00	80.50	4.00 +
लिप्टन	79.50	55.00	62.00	3.00 +
लोहिया-मशीन्स	32.00	7.75	13.50	1.00 +
महिंद्रा-महिंद्रा	61.00	38.00	55.00	2.00 +
मेकडोवेल	108.50	41.50	84.00	0.50 +
मोटर इंडस्ट्रीज	695.00	317.50	537.50	36.25 +
मुकुंद आयरन	89.50	62.00	79.50	4.50 +
नेशनल आर्गेनिक	577.50	382.50	490.00	30.00 +
निरलॉन	26.00	5.00	8.25	0.25 +
ओरके सिल्क मिल्स	115.00	19.65	25.50	0.50 +
ओसवाल आग्रो	142.00	79.00	126.00	3.25 +
पेइको इलेक्ट्रॉनिक्स	57.25	31.50	32.50	1.00 —
ओटिस एलिवेटर	260.00	155.00	215.00	15.00 +
प्रीमियर ऑटो	33.00	17.00	26.00	0.50 +
रैनबेक्सी	135.00	71.00	100.00	23.00 +
रेमंड	109.00	48.00	92.00	5.00 +
रिलायंस इंडस्ट्रीज	277.00	92.00	116.00	9.00 +
रिचर्डसन हिंद	350.00	210.00	304.00	29.00 +
श्रीराम फाइबर्स	36.00	19.50	41.00	9.75 +
सैंडोज	140.00	57.50	72.50	6.25 +
शॉ वैलेस	158.50	101.00	124.00	10.00 +
सीमेन्स इंडिया	144.50	64.00	74.00	1.00 —
स्मिक	53.50	26.00	33.25	4.75 +
स्टील	1207.50	500.00	662.50	70.00 +
टेल्को	665.00	330.00	343.00	17.00 —
विम्को	56.50	18.00	20.75	0.75 +

भारतीय रुपए का मूल्य

देश	मुद्रा	इकाई	बिक्री मूल्य (रुपए में)	क्रय मूल्य (रुपए में)
आस्ट्रेलिया	डालर	1	9.3390	9.2400
आस्ट्रिया	शिलिंग	1	1.1465	1.1342
बहरीन	दीनार	1	34.2232	34.2781
बांग्लादेश	टका	100	41.7500	41.3622
कनाडा	डालर	1	10.1765	10.0719
डेनमार्क	क्रोनर	1	2.0948	2.0724
मिस्र	पौंड	1	9.6190	9.5837
फ्रांस	फ्रैंक	1	2.4271	2.3657
हांगकांग	डालर	1	1.6873	1.6704
इंडोनेशिया	रुपिया	100	0.0790	0.0758
ईरान	रियाल	100	19.4210	19.3718
इटली	लीरा	100	1.0900	1.0732
जापान	येन	100	10.4000	10.1500
केन्या	शिलिंग	1	0.7800	0.7481
कुवैत	दीनार	1	40.9710	40.8132
मलेशिया	डालर	1	5.2194	5.1657
मारीशस	रुपया	1	1.0630	1.0410
नेपाल	रुपया	1	0.6197	0.6001
हालैंड	गिल्डर	1	7.1685	7.0937
पाकिस्तान	रुपया	1	0.7410	0.7210
सिंगापुर	डालर	1	6.5081	6.4405
स्पेन	पेसो	1	0.1176	0.1169
श्रीलंका	रुपया	1	0.4200	0.4000
स्वीडन	क्रोनर	1	2.2246	2.2007
स्विट्जरलैंड	स्विस फ्रैंक	1	9.8834	9.7782
तंजानिया	शिलिंग	1	0.2100	0.1958
थाईलैंड	बहत	100	52.0000	51.5000
ब्रिटेन	पौंड	1	23.9750	23.8400
सं. राज्य अमेरिका	डालर	1	13.1400	13.0100
सं. अरब अमीरात	दिरहाम	1	3.5500	3.4661
सोवियत संघ	रूबल	1	16.9375	16.8919
पश्चिम जर्मनी	जर्मन मार्क	1	8.1967	7.9936

स्रोत—बैंक ऑफ टोक्यो, नई दिल्ली, 7.1.88

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भागिए

यह कूपन और अपनी चहेती आवाज़ सुनिए: बच्चे की खिलखिलाहट

ख़ुश होते . . . मौज मस्ती करते बच्चों को देखना आपको ख़ुश करने के लिए काफ़ी है. बच्चों के लिए जितने ज़रूरी हैं खाना-पीना और हवा उतनी ही ज़रूरी है हंसी-ख़ुशी . . . मौज-मस्ती. और डिस्नी टुडे लेकर आया है यही मस्ती . . . यही मज़े. एकदम वैसी ही कॉमिक पत्रिका जो हर बच्चे के विकास के लिए ज़रूरी है. आख़िर डिस्नी गैंग के सदस्य दुनिया भर के अरबों बच्चों के चहेते हैं . . . मनपसंद हैं.

बस तो फिर यह कूपन भर दीजिए और हर एक को ख़ुश कर दीजिए.

यही है अद्‌भुत तरीका बच्चों को यह जताने का कि वे आपकी ज़िंदगी में सदा-सदा सबसे महत्वपूर्ण रहेंगे. सबसे बढ़िया बात यह कि घर भर में गूंज उठे आपकी चहेती आवाज़.

आपके बच्चे की खिलखिलाहट.

आज ही सबस्क्रिपशन भेजिए और आकर्षक छूट का लाभ उठाईये.

कूपन निम्नलिखित पते पर भेजें :
लिविंग मीडिया इंडिया (प्रा.) लि०
सबस्क्रिपशन डिपार्टमेंट
थॉमसन प्रेस बिल्डिंग
पो.बॉ. न. 69 दिल्ली-मथुरा रोड
फ़रीदाबाद- 121 007 (हरियाणा)

WM COMICS

डिस्नी टुडे

अब उपलब्ध हर पखवाड़े हिंदी और अंग्रेज़ी में.

मुझे अपने बच्चे के लिए सबस्क्रिपशन चाहिए. यह रहा मेरा
☐ सालाना: रु. 78/- ☐ छह महीने का: रु. 40/- हिन्दी
प्रति के लिए सबस्क्रिपशन. मैं भुगतान चैक/मनी आर्डर/ डिमांड ड्राफ्ट नं _____ द्वारा कर रहा हूँ.
कृपया प्रति निम्नलिखित नाम व पते पर भेजें:
नाम _____
उम्र _____ लिंग _____
डाक-पता _____
_____
_____
विद्यालय: _____
माता-पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर _____
कृपया भुगतान लिविंग मीडिया इंडिया (प्रा०) लि० के नाम पर बनाएं.

114

© 1987 THE WALT DISNEY CO., USA.

MILESTONES/DT/114 Hn

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शहरीकरण

खस्ता जिंदगी,

दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पद का जिम्मा संभालने के दो साल बाद ओम कुंमार को इस सचाई का एहसास हो गया है कि किसी भारतीय शहर के प्रबंध में "जहां कहीं खराबी की संभावना है वहां खराबी होना तो बस तय ही है."

बंबई का ही उदाहरण लें, ठीक यही हाल चल रहा है इस महानगर में. मस्जिद बंदर के व्यस्त इलाके में पिछले पखवाड़े की एक सुबह शक्तिहीन हो चुकी 'शक्ति निवास' नामक इमारत ढह गई जिससे 26 लोग मारे गए और छह गंभीर रूप से घायल हो गए. यह इमारत 40 साल पुरानी थी और उसे मरम्मत की सख्त जरूरत थी. पिछले साल नगर निगम ने एक सर्वे में पाया था कि इस महानगर में 16502 बहुमंजिली इमारतें 50 साल से ज्यादा पुरानी हैं और कभी भी गिर सकती हैं.

पूरब के महानगर कलकत्ता में सभी सरकारी दफ्तर सुबह 10 बजे खुल जाते हैं. मगर धोतीधारी मानिक चटर्जी 10.45 पर राज्य सचिवालय की जर्जर सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, बदरंग थूकदान में पान की भरपूर पीक थूकते हैं और दफ्तर में प्रवेश करते हैं. चटर्जी 45 मिनट लेट हैं, फिर भी दफ्तर में वे ही सबसे पहले पहुंचे हैं. वे कहते हैं, "लेकिन देर से पहुंचने पर कोई अफसर शिकायत नहीं करता क्योंकि वे जानते हैं कि शहर की यातायात व्यवस्था कितनी खराब है."

उधर दक्षिण में मद्रास में पिछले महीने उत्तर-पूर्वी मानसून के आगमन की सूचना देती पहली मूसलाधार बारिश हुई तो शहर के 39 लाख बाशिंदों ने सोचा कि अब पानी का संकट खत्म हो जाएगा. लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी. पिछले हफ्ते वाटर बोर्ड अध्यक्ष जी. वरदराजुलु ने उन्हें दुखदाई सूचना दी कि शहर के 35 प्रतिशत भंडारण जलाशय ही भरे हैं और लोगों को पानी सप्ताह एक-एक दिन छोड़कर ही मिलेगी. पानी के अभाव से जूझ रहे पश्चिम मंबलम की आजिज आ चुकी एक गृहिणी इंदिरा वैद्यलिंगम कहती हैं "मैं रोज पति का सिर खाती हूं कि किसी और शहर में काम तलाशें."

और यह बदहाली सिर्फ बड़े शहरों की ही बात नहीं है. देश के सभी 3245 शहर और कस्बे इस रोग से ग्रस्त हैं. दिल्ली के एक नगर नियोजन विशेषज्ञ जे.सी. गंभीर कहते हैं, "शहरों में आज ऐसे

प्रशांत पंजियार

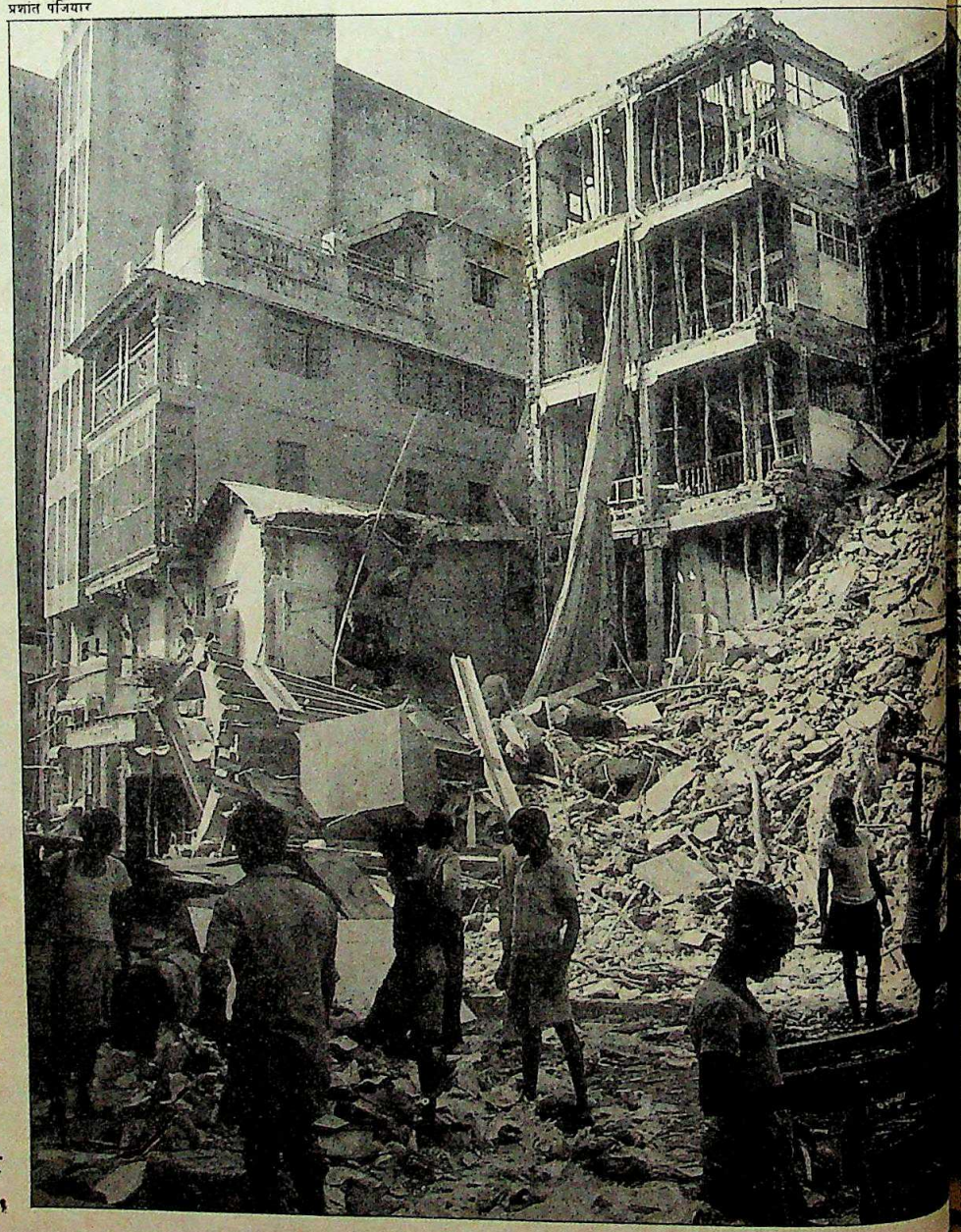

बंबई में 'शक्ति निवास' जैसी जर्जर 16000 इमारतें और भी हैं

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बदहाल नगर

चुनौतियां हमारे सामने हैं मानो युद्ध जैसी स्थिति हो. गांवों से आबादी शहरों की ओर चली आ रही है जिसने नागरिक सेवाओं का कचूमर निकाल दिया है. अगर हम जल्दी ही कुछ नहीं करते तो विनाश की ओर बढ़ जाना तय है.''

देश के इतिहास में कभी भी शहरीकरण की ऐसी लहर नहीं देखी गई थी. प्रति वर्ष अनुमानतः 50 लाख गांववाले अपने पीछे सूखी जमीन व टिमटिमाते दीप छोड़कर रोजगार की तलाश में दूर शहर की दमकती रोशनियों की ओर बढ़ जाते हैं. स्वाधीनता के बाद से देश की शहरी आबादी चार गुना—5 करोड़ से 20 करोड़ (पिछले साल तक)—बढ़ गई है. देश की कुल आबादी का चौथाई हिस्सा अब शहरों में आ बसा है. 1991 तक भारत के 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले महानगरों की संख्या 12 से बढ़कर 20 हो जाएगी. इनमें कलकत्ता और बंबई की आबादी तो एक करोड़ को भी पार कर जाएगी.

विकास की अगुआई करने के बजाय ये शहर कथित विकास के बोझ तले खुद ही चरमराते जा रहे हैं. स्थानांतरण की अंतहीन लहर से ज्यादातर शहर अमानवीय गंदी बस्तियों में बदल गए हैं. आवास की समस्या बढ़ने से आधी आबादी एक कमरे की झोंपड़ियों में नारकीय जीवन जी रही है और बाकी लोग करीब-करीब एक-सी दिखने वाली बहुमंजिली इमारतों में बसर कर रहे हैं.

नागरिक सेवाएं दम तोड़ रही हैं. खचाखच भरी बसें, सड़कों पर मची अराजकता, पानी के लिए लंबी कतारें, बदबू छोड़ती नालियां और अरसे से जमा होते कूड़े के ढेर जैसे अनिष्टकारी भविष्य का ही संकेत देते हैं. संस्कृतियों की यह शहरी घिचपिच अब नासूर बनती जा रही है. रोंगटे खड़े कर देने वाली इन मुसीबतों के बीच चंद लोगों द्वारा दौलत के दिखावे के कारण सामाजिक तनाव बढ़ रहे हैं. शहरों में मामूली-सी वजहों से दंगे भड़क उठते हैं, अपराध बढ़ रहे हैं और इस दुःस्वप्न को भूलने के लिए युवा पीढ़ी नशीले पदार्थों के आत्मघाती कुंड में गोते लगा रही है.

देहातों से लोगों के आने की वजह केवल शहरों का चुंबकीय आकर्षण ही नहीं है. शहर नियोजक अब बताते हैं

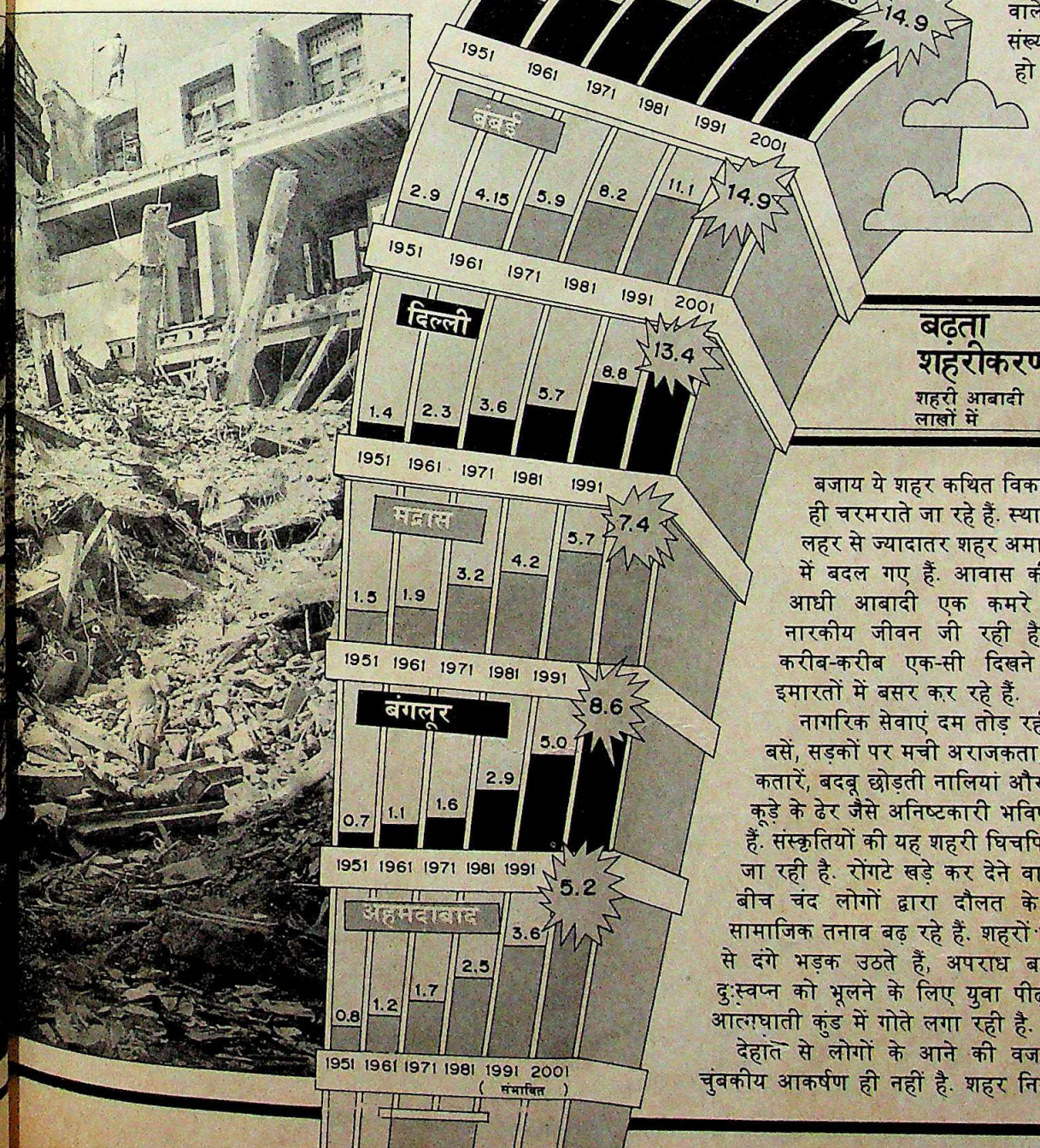

बढ़ता शहरीकरण

शहरी आबादी लाखों में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कि गांवों में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ रही है, खेती से गुजर कर पाना दूभर होता जा रहा है जिसकी वजह से यह पलायन हो रहा है. बंबई के समाजशास्त्री चंदन सेनगुप्त इन शब्दों में इसका चित्र खींचते हैं, "कई हजार जीवन-रक्षक नौकाएं कुछ इने-गिने टापुओं की ओर बढ़ रही हैं. उनके लिए यह अस्तित्व का सवाल है."

ग्रामीण वोटों की भारी संख्या के मद्देनजर सत्ता में बैठे नेताओं और साथ ही केंद्र सरकार का रवैया शहरीकरण के प्रति शुतुरमुर्ग जैसा रहा है. इस उम्मीद में वह मामले की अनदेखी करती रही है कि शहर किसी न किसी तरह अपनी समस्याओं से निबट ही लेंगे. जैसा कि एक प्रमुख शहर नियोजक एम.एन. बुच कहते हैं, "हमारी शहरीकरण की कोई नीति ही नहीं रही है. हमारा रवैया यह रहा है कि बंबई चूंकि बड़ा शहर है और उसकी अपनी जरूरतें हैं, इसलिए प्रधानमंत्री वहां जाते हैं और 100 करोड़ रुपए मंजूर करके चले आते हैं. या फिर कलकत्ता तो चूंकि एक मरता हुआ शहर है इसलिए चलो वहां हम एक पुल और बनवा देते हैं. कुल मिलाकर सारी योजना तदर्थवाद पर ही चल रही है."

गांव से पलायन करके आने वाले लोगों को कस्बों में बसाने की कोई कोशिश नहीं हो रही है जिससे महानगर और विकराल होते जा रहे हैं. ज्यादातर महानगरों की आबादी सालाना 4 से 7 प्रतिशत तक बढ़ रही है. आबादी वृद्धि की यह रफ्तार राष्ट्रीय जनसंख्या वृद्धि दर से भी दुगुनी है. बंबई में हर महीने 25,000 लोग बाहर से आ जाते हैं. और दिल्ली में बाहर से आने वालों की संख्या 1.2 लाख सालाना है.

सबसे स्पष्ट दरार तो ज्यादातर शहरों में हुआ गंदी बस्तियों का विस्फोट है जो शहरी अवनति और गरीबी की प्रतीक बन गई हैं. गांवों की विपन्नता से स्थानांतरित लोगों की लंबी शृंखला शहरों में कहीं भी टीन की चादरों और टाट व बोरी से झोंपड़ी डालकर आसानी से डेरा जमा लेती है. केंद्र सरकार के मुताबिक विभिन्न शहरों में झुग्गीवालों की संख्या तीन करोड़ से ज्यादा है. चार बड़े शहरों—बंबई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास—में अब अनुमानतः एक-तिहाई आबादी गंदी बस्तियों में रहती है (देखें चार्ट).

दिल्ली में एक तरफ तो आलीशान फ्लाईओवर और हरे-भरे बगीचे हैं तो दूसरी ओर बाहरी दिल्ली में जीवन नरक बना हुआ है. पूर्वी दिल्ली के यमुना पार के इलाकों—नंद नगरी व सीमापुरी—में मनुष्य और पशु एक-सा जीवन जीते हैं. खुली, बदबूदार और भरी हुई नालियों में बहता मानव-मल सड़कों पर छलक आता है, कूड़ा बीनने वाले और चूहे कूड़े के ढेरों पर पिले दिखाई देते हैं, सुअर गंदगी में लोटते हैं, सार्वजनिक नलों पर मीलों लंबी कतारें दिखती हैं, और जब रात घिर आती है तो लोग चिथड़ा-चिथड़ा हो चुके तिरपालों के नीचे पसर जाते हैं. दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड से मुकाबला करने के लिए उनके पास एक ही कंबल होता है—रद्दी अखबारी कागजों का.

शहरी गरीबी की यह बीमारी दूसरे शहरों में भी फैल चुकी है. अहमदाबाद पिछले दशक में सबसे तेजी से बढ़ने वाले पांच महानगरों में रहा. अब वहां 700 से ऊपर गंदी बस्तियां हैं. स्थानांतरित लोग को जहां भी जमीन खाली दिखी, वहीं बस गए. पूर्वी अहमद

झोपड़पट्टी: गांवों से पलायन के बाद आश्रय स्थल

प्रभात

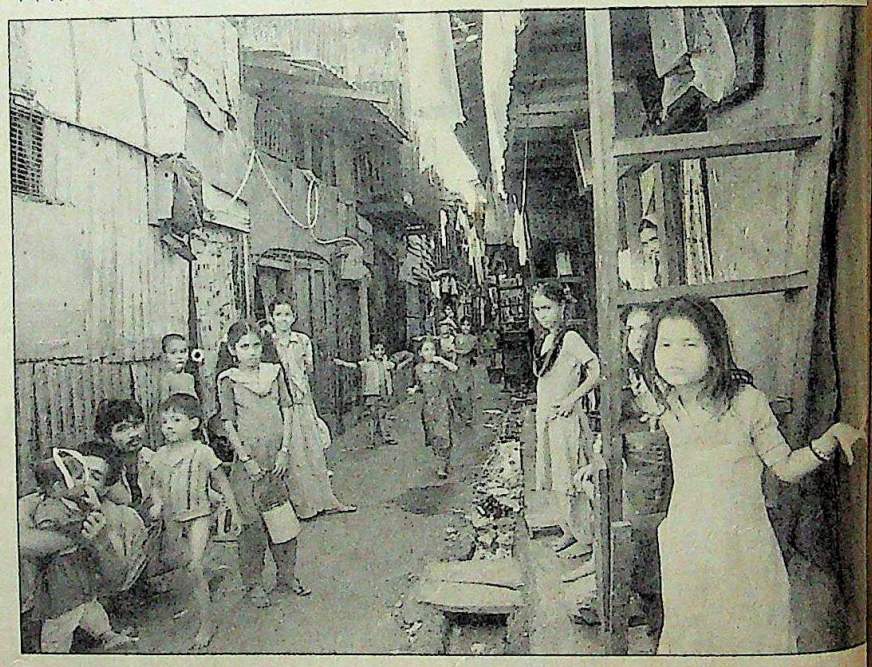

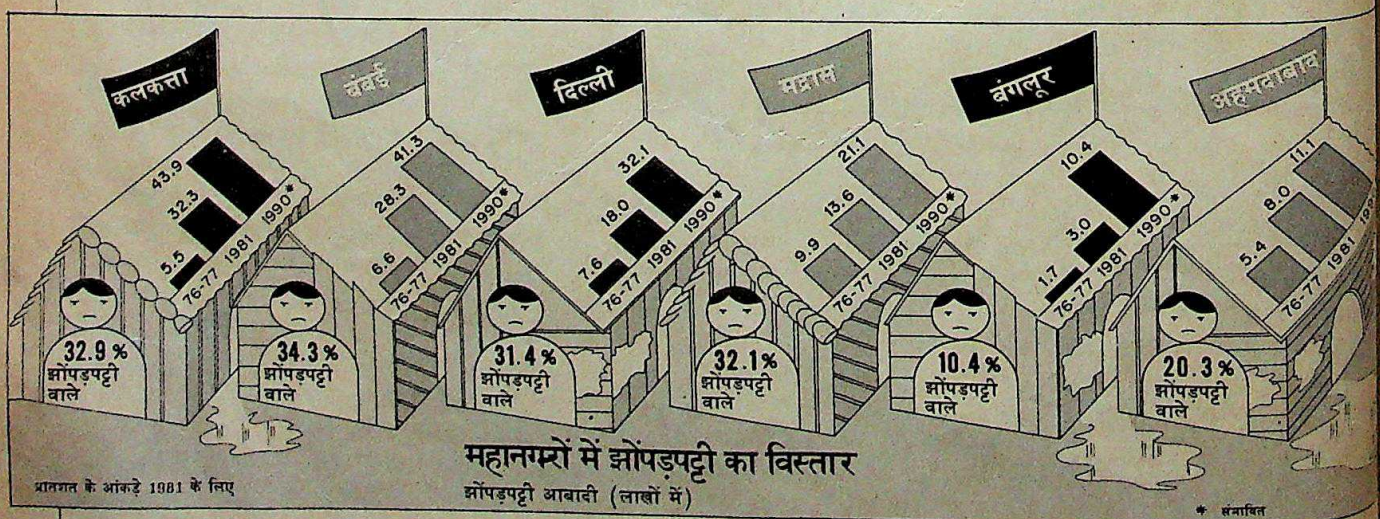

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बंबई की धारावी

नौ गज जमीं के लिए...

मैं बंबई क्यों आया? मेरा जन्म अलीगढ़ में एक गरीब परिवार में हुआ था. आजीविका कमाने के लिए ही एक दिन पंजाब मेल में बैठकर मैं यहां चला आया. मुझे वे दिन आज भी याद हैं, दिन भर मैं अब्दुल रहमान स्ट्रीट पर तालों की एक दुकान में काम करता और रात को थककर ठेला गाड़ी पर सो जाता.

"कुछ वर्ष बाद मैं सपरिवार महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन के पुल के नीचे रहने लगा. मेरे एक मित्र ने मुझे सलाह दी कि मैं चाहूं तो धारावी में उसकी झोंपड़ी के पास की खाई को पाटकर अपनी एक झोंपड़ी बना लूं. जगह दलदल भरी थी. उसमें तीन ट्रक मिट्टी डालने के बाद हम वहां यह छोटी-सी झोंपड़ी डाल पाए.

"इस बात को आज 17 वर्ष बीत चुके हैं. इस दौरान धारावी क्षेत्र में बहुत परिवर्तन हुए हैं. यहां की आबादी बढ़कर लगभग चार गुना हो गई है. यहां करीब पांच लाख लोग रहते हैं."

यह सब बताते हुए 48 वर्षीय अब्दुल मजीद अंसारी फैशनेबल खूंटियों, दरवाजों की कुंडियों और चिटखनियों पर हथौड़ी चलाना जारी रखता है. हथौड़ी की आवाज 10 × 8 फुट की कोठरी में टीन की छत और दीवारों से टकराकर गूंजती है पर उससे कोठरी के पिछवाड़े चलती सिलाई मशीनों की घरघराहट नहीं रुक पाती. उधर उसकी 45 वर्षीय बीवी अंसारी बेगम और दोनों बेटियां फरजाना (29) और रुखसाना (22) सलवार कमीजों की सिलाई में व्यस्त हैं. खोली में एक परछत्ती है जहां वे लोग अपना सामान रखते हैं और बरसात के दिनों में जब घरों-कूचों में पानी भर जाता है तो वही उनका कमरा भी बन जाता है.

अंसारी धारावी के संजय चाल मुकुंद नगर में रहता है. एशिया की इस सबसे बड़ी गंदी बस्ती में कई कॉलोनियां हैं. बरसाती पानी के नाले और सार्वजनिक शौचालय ही उन्हें एक दूसरे से अलग करते हैं. अधिकांश घर ईंट और टीन के बने हुए हैं. तकरीबन हर घर में छोटा-मोटा वर्कशॉप है जहां पापड़ से लेकर धातु के ड्रम और जरी के कपड़े बनाने तथा चमड़ा पकाने का काम होता है. अंसारी लगभग 1500 रुपए प्रतिमाह कमा लेता है. उसकी पत्नी तथा लड़कियां भी कपड़ों की सिलाई करके इसमें योगदान देती हैं.

"हम सब मिलकर गुजारे लायक कमा लेते हैं. लेकिन बदकिस्मती से मेरा दामाद ठीक नहीं निकला. मेरी बड़ी बेटी तो खैर अब यहीं बस गई है, छोटी भी अलीगढ़ वापस नहीं जाना चाहती. बंबई जैसी आजादी उसे कहां मिलेगी."

अंसारी इस क्षेत्र में आठ साल पहले गठित एक कल्याणकारी संस्था 'प्राउड' का सक्रिय कार्यकर्ता है. वह बड़े उत्साह से बताता है कि इसी संस्था के प्रयत्नों की बदौलत ही यहां सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण हो पाया है. अपनी बात अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए लोगों ने पहले लकड़ी का एक सांकेतिक शौचालय बनाकर बस्ती के पास वाली सडक को बंद किया. उसके बाद थैलों में गंदगी और कीड़े भरकर नगर निगम अधिकारियों की मेजों पर रखे गए. तब उनकी बात सुनी गई.

लेकिन सरकारी अधिकारी शायद कभी नहीं सुधरेंगे. धारावी सुधार के लिए प्रधानमंत्री की 37 करोड़ रुपए की योजना की दुर्गति इसका स्पष्ट प्रमाण है. अंसारी कॉलोनी के बीचोबीच खुले नाले की ओर इशारा करते हुए कहता है कि इसका निर्माण पानी की निकासी के लिए किया गया था. अब इसमें कूड़ा-करकट भरा हुआ है.

"इस प्रकार पैसे बरबाद किए जाने की कोई तुक नहीं है. यदि सरकार चाहे तो हम लोगों की मदद ले सकती है. पैसे का सदुपयोग करके इस बस्ती का उद्धार किया जा सकता है. अब हम कहीं और तो जाने से रहे. संघर्ष करके यहीं सब कुछ—पानी, बिजली, शौचालय हासिल कर लिए हैं.

"यदि सरकार हमारी मदद करे तो हमें कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं रहेगी. हमारी बस्ती में सारी सुविधाएं मौजूद हैं—रोजगार, डॉक्टर, स्कूल, मंदिर, मस्जिद, रेस्तरां और अब तो एक वीडियो पार्लर भी यहां खुल गया है. लेकिन वीडियो हमारे लिए अभिशाप सिद्ध हो रहा है. बच्चे पढ़ाई के बजाय फिल्में ज्यादा देखते हैं. उन्हें ब्लू फिल्मों की लत भी लग गई है.

"अलीगढ़ में जीवन अधिक शांत है, लेकिन मैं वहां नहीं जाना चाहूंगा. वहां इतने पैसे ही नहीं कमा पाऊंगा. यह ठीक है कि बंबई में 100 रुपए कमाकर 80 खर्च करने पड़ते हैं. मेरे पास थोड़े और पैसे जमा हो गए तो मैं अपने घर को दुमंजिला कर लूंगा. हमारी झोंपड़ियों को कानूनी मान्यता भी मिल सकती है. पर मैं तो काम करने में ही विश्वास रखता हूं, जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए काम से बढ़कर कुछ नहीं."

—एम. रहमान

अपनी खोली में अंसारी: 'अब अलीगढ़ नहीं लौटूंगा'

प्रशांत पंजियार

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बाद—जिसमें नारौल, सैजपुर-भोगा, ओधा, वातवा आदि इलाके हैं—शहर के हरित पट्टी क्षेत्र के रूप में निर्धारित था, लेकिन आज इस पूरे क्षेत्र में झुग्गी-झोंपड़ियों की लंबी कतारें हैं और शहर का हर दूसरा व्यक्ति गंदी बस्तियों का निवासी है.

झोपड़पट्टियों की बाढ़ को रोकने के लिए कुछ करने के बजाय स्थानीय नेताओं और अफसरों ने झुग्गियों के 'दादा' लोगों से सांठगांठ करके गंदी बस्तियों का उद्धार नहीं होने दिया. विडंबना देखिए कि उनकी इस करतूत में 1976 का शहरी भूमि हदबंदी कानून ही सहायक बना. वैसे तो यह कानून हदबंदी से ज्यादा की जमीन अधिग्रहीत करके भूमि की कमी दूर करने और जमीन की खरीद-फरोख्त में चलने वाले सट्टे के धंधे को बंद करने के लिए बना था. लेकिन अब इसी की आड़ में अवैध धंधा चल रहा है.

इस कानून के तहत सरकार बहुत कम जमीन अधिग्रहीत कर पाई (मिसाल के तौर पर दिल्ली में सिर्फ दो एकड़ और कलकत्ता मे 34 एकड़). उलटे कानून से धंधेबाज लोगों को ही फायदा पहुंचा. जिनके पास ज्यादा जमीन थी उन्होंने उसका बंटवारा कर दिया और पलायन करके आए लोगों को जमीन बेच दी. इसके बाद मालिकों ने अपने राजनैतिक संपर्कों या 'झुग्गियों के दादा' कहलाने वालों का इस्तेमाल किया ताकि कोई उन्हें उनकी जमीन से हटाने की जुर्रत न करे. जैसा कि गुजरात स्लम क्लियरेंस बोर्ड के नियोजन अधिकारी बी.डी. शुक्ला कहते हैं, "शहरी भूमि हदबंदी कानून हमारे लिए एक बड़ा सिरदर्द है. मालिक अपनी अतिरिक्त जमीन से ज्यादा से ज्यादा कमाई करने के लिए कोई भी रास्ता अख्तियार करने पर उतारू हैं जिससे गंदी बस्तियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है."

मकानों की मांग बढ़ने और उनके अभाव के कारण जाहिर है जमीन की कीमतें आसमान छू रही हैं. यहां तक कि गोदाम, गैरेज, मकान के बाहर बने शौचालय तक को रहने के काबिल बना दिया गया है. बंगलूर के भीड़भाड़ वाले जे.सी. रोड के पीछे एक दड़बेनुमा कमरे में एक क्लर्क के. बालाचंद्रन अपने चार-सदस्यीय परिवार के साथ बसर करते हैं. उनका मकान मालिक इस कमरे को फ्लैट कहता है और इसके लिए उनसे 650 रुपए किराया वसूलता है. पर बालाचंद्रन परिवार इतनी कम जगह में गुजर-बसर करने के गुर अच्छी तरह जान गया है—सुबह वह कमरा रसोईघर बन जाता है और रातों में फर्श पर दरियां डालकर उसे सोने के कमरे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है.

लेकिन मकानों की जैसी कमी बंबई में है वैसी कहीं भी नहीं. एक समय था जब इस शहर में मध्यमवर्ग का वर्चस्व था और आकर्षण का

चरमराती नागरिक सेवाएं

ऐसे परिवारों का प्रतिशत जिन्हें बिजली, नल और शौचालय हासिल नहीं

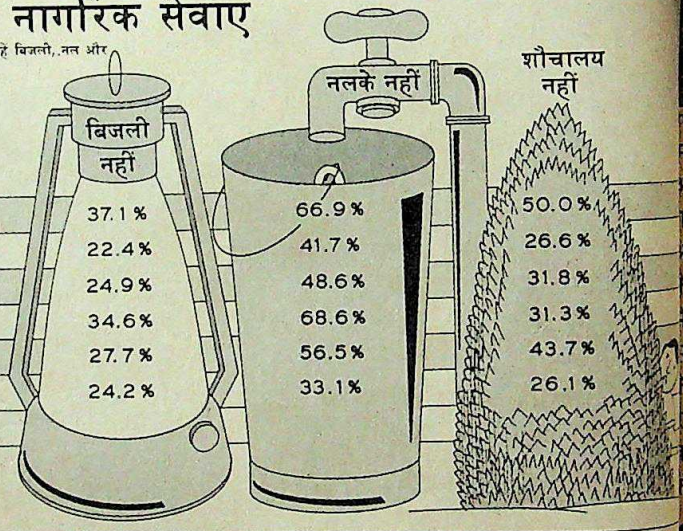

मद्रास में पानी के लिए लाइनः पानी भी रोज नहीं मिलता

श्याम टेकवानी

केंद्र कुछ अमीर बस्तियां थीं. इससे शहर का चरित्र नियत होता था. मालाबार और कंबाला हिल्स जैसे पॉश माने जाने इलाकों तक की सर्वश्रेष्ठ इमारतों में भी दो कमरों का फ्लैट उन में 70 हजार रुपए में खरीदा सकता था. यह स्थिति '60 दशक तो थी ही. तब शहर आबादी 42 लाख थी और मुंबई से 12 प्रतिशत लोग झोंपड़ों में रहते थे. मगर इस परीकथा वहीं अंत हो गया.

अब बंबई में एक चाल 50,000 रुपए से कम में बिकती है. गरीबों को जहां बस्तियों में रहने को बाध्य पड़ा है, वहीं मध्यमवर्ग दूरदराज उपनगरों या उनसे भी आगे को मजबूर हो गया है. उदाहरण स्वरूप दस साल पहले ठाणे जि

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

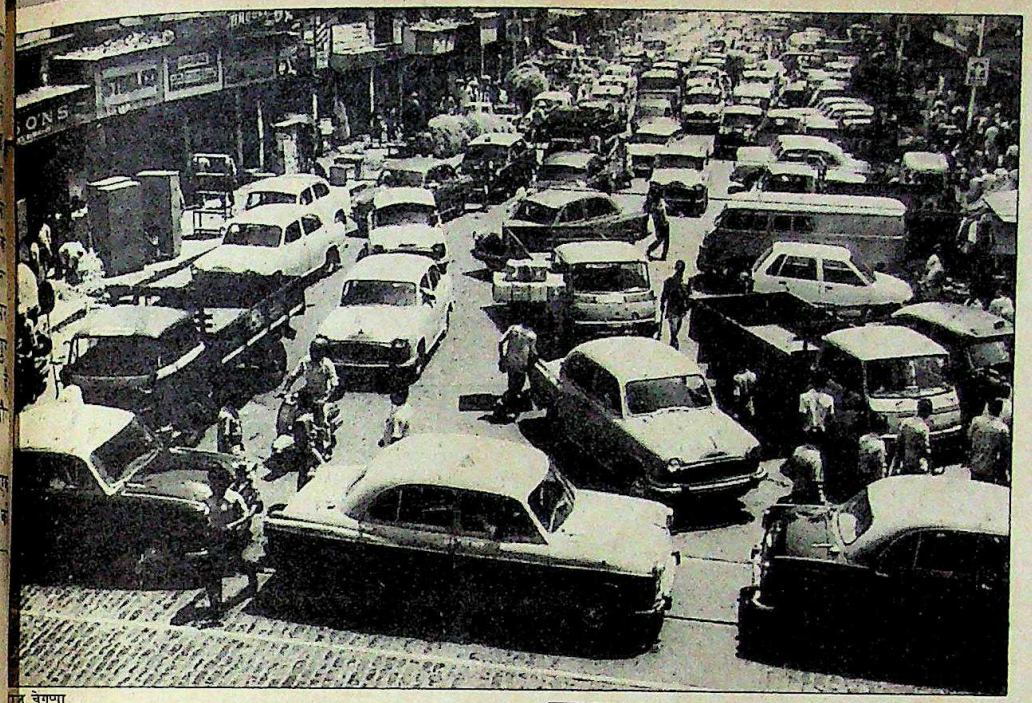

फोटो: चेंगप्पा

कलकत्ता में सड़क जाम: ठहर गई पूरी सदी

छुआरों का खूबसूरत वसई गांव अपने नूठे गिरिजाघरों व एक ध्वस्त पुर्त-ाली किले के लिए जाना जाता था. ाज वसई रोड स्टेशन पर, जहां बंबई चर्चगेट स्टेशन से ट्रेन से 70 मिनट पहुंचा जा सकता है, यात्रियों की ारी चहल-पहल रहती है जो पटरियों किनारे बनी बहुमंजिली इमारतों में हते हैं. अब वसई में 500 रुपए प्रति फुट की दर से फ्लैट बिकते हैं. उनकी मत 5 से 10 लाख के बीच है.

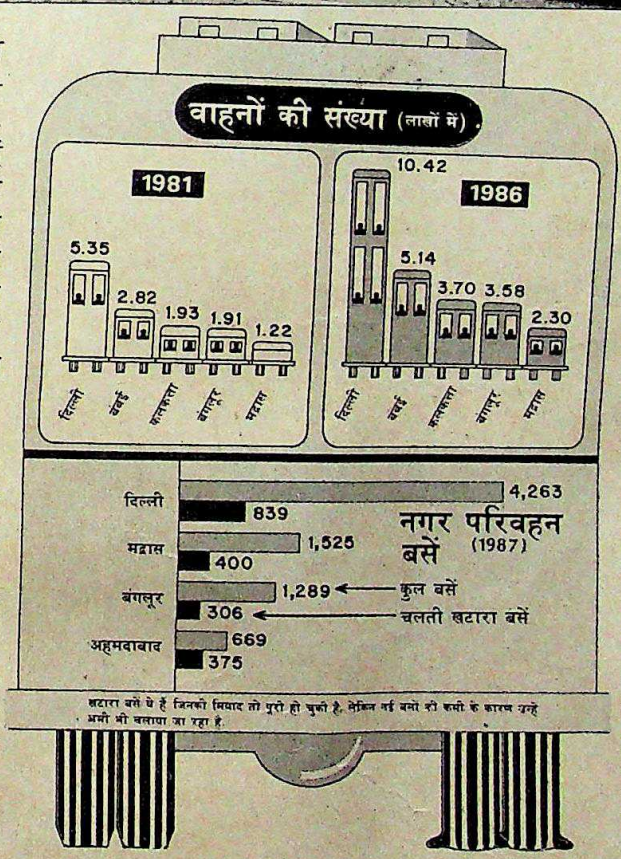

सिटी बसों व लोकल में रोजाना काम पर जाने और वहां से टने की यातनादायी यात्रा के परि-ाम भी अब सामने आने लगे हैं. न्यू बे के वाशी में रहने वाले एक सेल्स नेजर श्रीनिवास राजन (35) ायत करते हैं, "रोजाना तीन घंटे मैं सफर में ही गुजारता हूं. यह हुत ही हताशाजनक है. सुबह होते ही काम पर भागता हूं. ट्रेन या बस के ए इंतजार करना पड़ता है. शाम को र उसी तरह घर की ओर भागो. र जब आप थके हों तो इंतजार और यात्रा अंतहीन लगने लगती है. का असर मेरे पारिवारिक जीवन पर भी पड़ने लगा है. मुझे अपने बच्चों के साथ खेलने का समय मुश्किल से ही मिल पाता है. और इतवार का इंतजार करता हूं. लेकिन एक दिन तो नाकाफी है."

बंबई की तरह ही ज्यादातार शहरों को येन केन प्रकारेण विस्तार मजबूर होना पड़ा है. महानगरों के इर्दगिर्द बसते जा रहे नए नगरों ने भी शहरों की पहले से ही चरमरा रही परिवहन व्यवस्था दबाव बढ़ा दिया है. दिल्ली में केवल पांच बरसों में ही दिल्ली रिवहन निगम (डीटीसी) को अपनी बसों की संख्या बढ़ाकर दुगुनी कर देनी पड़ी है. इसकी बसें अब रोजाना 50 लाख लोगों को ढोती हैं. पर दुगुनी हो जाने के बावजूद डीटीसी की बसें दिल्ली के लोगों के लिए कम पड़ रही हैं.

डीटीसी के जनसंपर्क अधिकारी स्वतंत्र चोपड़ा कहते हैं, "बढ़ती रफ्तार के साथ हम कभी तालमेल नहीं बिठा सके हैं. कुछ मार्गों पर तो हम प्रत्येक मिनट में 11 बसें चलाते हैं. अगर यही रफ्तार रही तो हमारा समूचा ढांचा जल्दी ही चरमरा जाएगा." डीटीसी की एक तिहाई बसों की 'उम्र' हालांकि पूरी हो चुकी है, फिर भी निगम उन्हें चलाते रहने को मजबूर है क्योंकि मांग जबरदस्त है. बंगलूर की परि-वहन सेवा (बीटीसी) को अब 'बंगलूर टार्चर सर्विस' (बंगलूर तकलीफ सेवा) कहा जाने लगा है क्योंकि इसकी बसें लोगों से घंटों इंतजार करवाती हैं. और अहमदाबाद में कभी प्रतिष्ठित रही परिवहन सेवा भी अब अव्यवस्था के कगार पर पहुंच चुकी है. इसकी आधी से ज्यादा बसें पुरानी पड़कर खटारा हो चुकी हैं और वे चलते-चलते कहीं भी चूं बोल जाती हैं. और आगे बढ़ने से इनकार कर देती हैं.

और शायद इतना काफी नहीं, करेले पर नीम चढ़े की कहावत चरितार्थ करते हुए तमाम सरकारी दफ्तर और व्यापारिक प्रतिष्ठान शहरों के बीचो-बीच आ बस रहे हैं. मसलन कलकत्ता में दो वर्ग किलोमीटर के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र में सभी प्रमुख सरकारी दफ्तर और 500 से ज्यादा कंपनियों के दफ्तर हैं. अंदाजन 32 लाख लोग और इतने ही वाहन इस इलाके में रोजाना आते-जाते हैं.

इस इलाके की ओर आने वाली सभी सड़कें ठसाठस भरी रहती हैं. ठेलागाड़ियां, हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शे और साइकिल सवार जैसे भरी हुई बसों, ट्रामों व लारियों से आगे निकलने की होड़ में रहते हैं. सबसे ज्यादा तेज वाहन की रफ्तार भी यहां आठ किमी प्रति घंटा रहती है. "यह ऐसा ही है जैसे पूरी एक सदी सड़कों पर ठहर गई हो," शहर के मुख्य ट्रैफिक व परिवहन प्रबंधक अमिय बंद्योपाध्याय टिप्पणी करते हैं. सड़कें जाम होने के बावजूद हाल तक कलकत्ता ने अपने ट्रैफिक को वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्थित करने की बाबत कभी सोचा भी नहीं था.

लेकिन बंद्योपाध्याय को कलकत्ता के उन्मत्त ट्रैफिक के लिए कोई

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कारगर तरीका भी नहीं सूझ रहा. असल में शहर जिस तेजी से फैला, सड़कें उस हिसाब से चौड़ी नहीं हुईं. आज वे शहरी क्षेत्र का केवल छह प्रतिशत हिस्सा घेरती हैं और इसमें भी आधा फेरीवालों और अवैध कब्जा करने वालों से घिरा रहता है.

ज्यादातर शहरों में वाहनों की बढ़ रही भीड़भाड़ और कारखानों के धुंए की अधिकता के कारण प्रदूषण का स्तर अंतिम सीमाएं लांघ रहा है. कलकत्ता के डलहौजी, कालीघाट और भवानीपुर जैसे इलाकों में इसका स्तर बरदाश्त की सीमा से तीन गुना अधिक हो गया है.

आजकल दिल्ली में सुबह सूर्य के न दिखने का कारण कोहरा नहीं रह गया है बल्कि धूम कोहरा घंटों छाया रहता है. बंबई में वातावरण में शोर के स्तर की छानबीन के लिए मुकर्रर हाइकोर्ट की एक समि ने पाया कि शहर के ज्यादातर हिस्सों में विश्व स्वास्थ्य संगठन सुझाई अधिकतम सीमा (55 डेसीबल) के मुकाबले शोर का 57 से लेकर 91 डेसीबल तक था.

परिवहन की इस अराजकता का असर लोगों के दैनंदिन जीवन भी पड़ रहा है. कलकत्ता की एक गृहिणी अर्चना विश्वास को समय में जात्राएं देखने का शौक रहा है. वे कहती हैं कि अब जात्राओं तक पहुंचना इतना आसान नहीं रह गया है. वे बताती "मुझे बस से घर लौटने में ही दो घंटे लग जाते हैं और पति महो तो कभी भी शाम साढ़े सात बजे से पहले नहीं लौट पाते. ऐसे तैयार होकर 10 किमी दूर जात्रा देखने जाना कैसे हो सकता है? नतीजा यह है कि हम घर पर ही रह टीवी के उबाऊ कार्यक्रम देखते रहने को मजबूर हैं."

अगर यातायात का यह आलम है तो आबादी विस्फोट भी 'नागरिक सेवाओं पर बुरा असर डाल है.' केंद्रीय सरकार के राष्ट्रीय शहरीकरण आ (एनसीयू) के सचिव नरेश नारद का यही ख्याल नागरिक सेवाओं की विकराल मांग के कारण त नगरपालिकाओं की व्यवस्था टें बोल गई है. ज्याद शहरों में एक-चौथाई आबादी को न तो नलों से मिलता है और न ही उनकी बस्तियों में नालियां बन हैं. शहरी आबादी का एक तिहाई-हिस्सा तो रात अंधेरे में रहने पर मजबूर है (देखें चार्ट).

महानगरों में पीने के पानी की कमी पहले गर्मि ही हुआ करती थी, अब तो जैसे यह दस्तूर ही बन है. लेकिन मद्रास में तो हमेशा ही पानी का अकाल रहने लगा है. वहां रातों की नींद जैसे सपना बन ग इस शहर की एक गृहिणी इंदिरा वैद्यलिंगम कहती "पानी देर रात को आता है. मैं अपने दोनों बच्चो सुलाकर नल के पास खड़ी हो जाती हूं और बाल्टिया के लाती रहती हूं. घर का पूरा पानी भरने तक सु तीन बज जाते हैं और फिर सुबह छह बजे बच्चो स्कूल जाने के लिए जगाना होता है."

मद्रास में भले ही पानी की सप्लाई एक दिन छो होती हो, दूसरे शहरों में स्थिति थोड़ी बेहतर है. में अब दिन-रात मिलाकर 22 घंटों तक पानी रहता है. पर लखनऊ में हाल बुरा है. वहां नलों में टपकता भर ही है. पटना का हाल सबसे बुरा है. पानी हर कहीं है, पर पीने लायक नहीं. हालांकि शहर गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है, इसकी आधी आबादी को पीने का पानी उपलब्ध नहीं साल पहले विधानसभा में सरकार ने स्वीकार कि कि पानी के 40 नमूनों का परीक्षण किया गया 16 से 40 प्रतिशत पानी प्रदूषित पाया गया.

शहर जहां पानी सप्लाई की समस्या से जूझ वहीं उनमें ज्यादातर लाखों गैलन जहरीले म परिशोधित करने की ओर ध्यान नहीं दे रहे. कलक बंटाला स्थित प्राथमिक ट्रीटमेंट प्लांट (भगव जानता है कब से) बंद पड़ा है और सारा मल कुल्टी

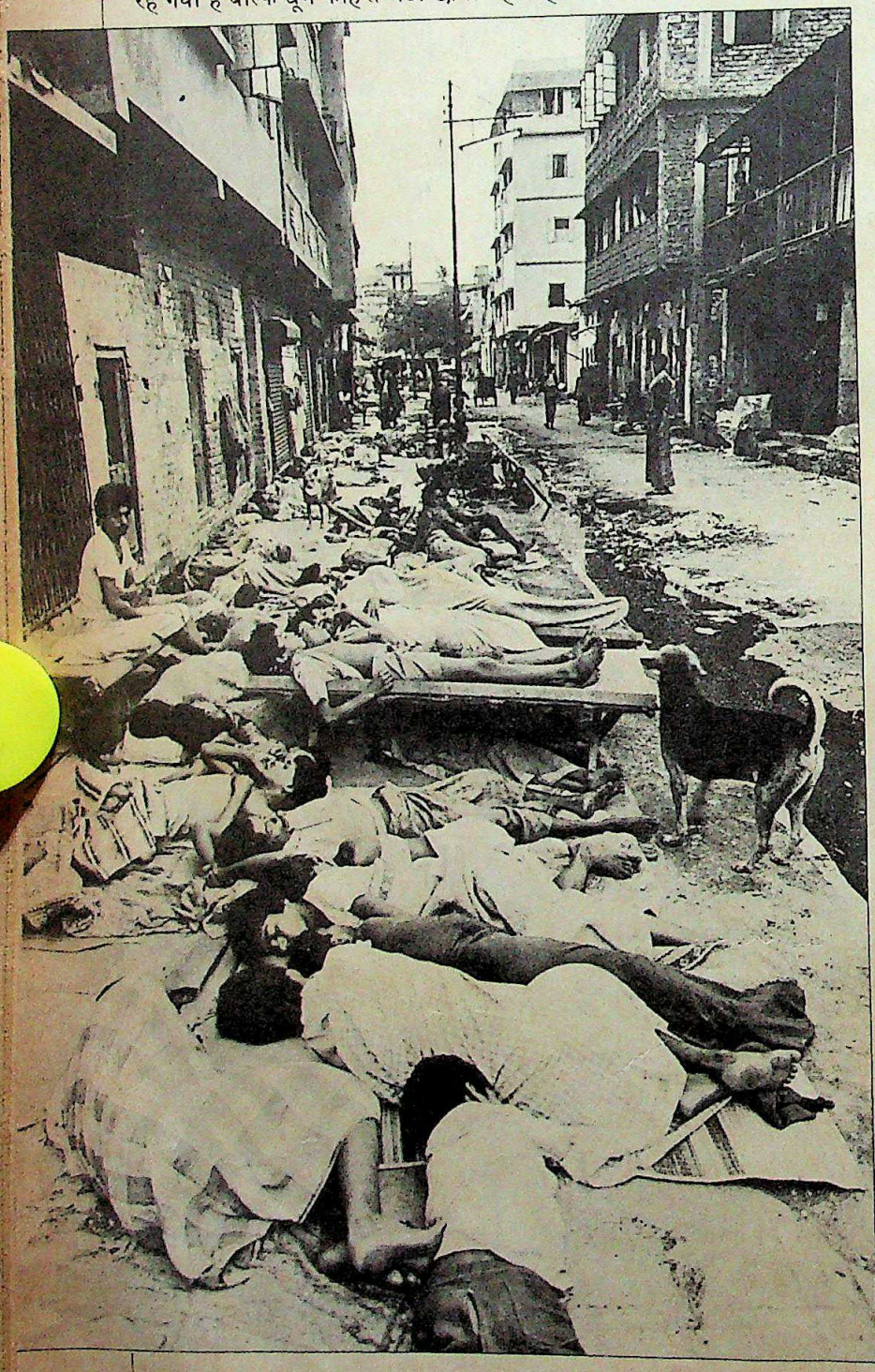

फुटपाथ पर सोने वालों की कतारें: अभावग्रस्त जीवन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

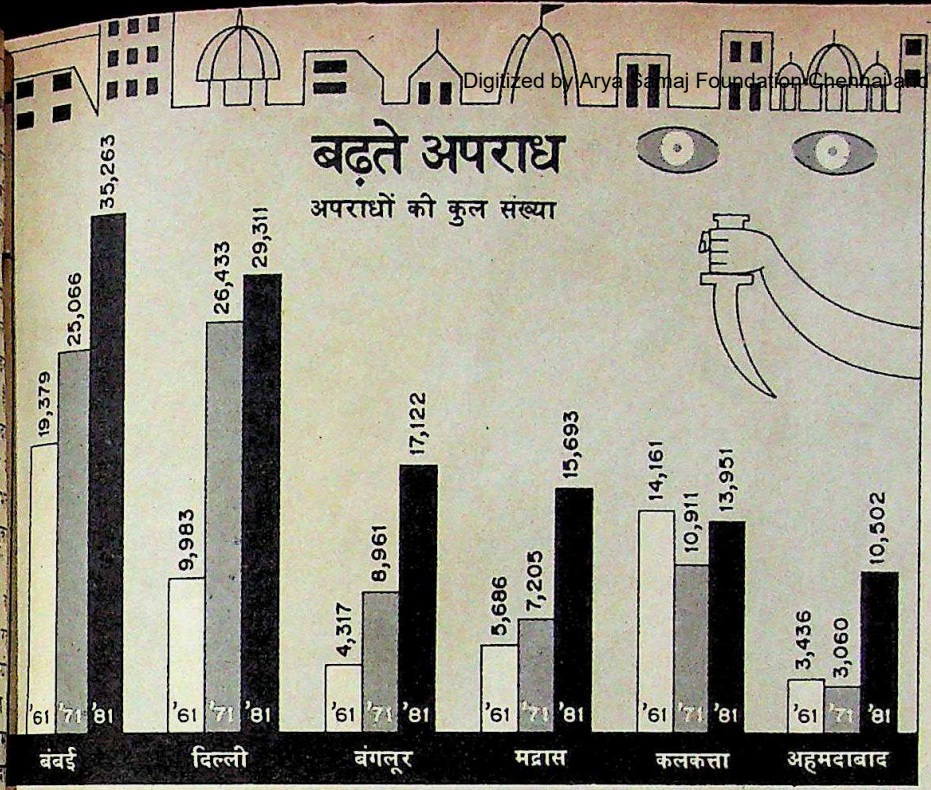

में डाल दिया जाता है, जो उसे बंगाल की खाड़ी में ले जाती है. इसी तरह अहमदाबाद का दो-तिहाई मल साबरमती नदी में डाल दिया जाता है जिससे यह कई किमी आगे तक प्रदूषित रहती है. यहां तक कि दिल्ली में भी नगर निगम मल का आधा ही परिशोधित करता है और बाकी यमुना में फेंक दिया जाता है जो इस नदी को मथुरा तक प्रदूषित किए रहता है.

पटना शहर तेजी से भारत का कूड़ा शहर बनने की ख्याति प्राप्त कर रहा है, जैसा कि एक स्थानीय सांसद डॉ. सी.पी. ठाकुर ने इसे संज्ञा दी है. शहर में प्रतिदिन एक फुटबाल के मैदान को भरने लायक कूड़ा इकट्ठा हो जाता है. पटना नगरपालिका के पास इसे साफ करने के लिए 58 ट्रैक्टर और 5,000 सफाई कर्मचारी हैं. लेकिन हाल के एक सर्वेक्षण से कई अजीबोगरीब बातें सामने आईं. नगरपालिका के 16 ट्रैक्टर ही काम के लायक हैं तथा कुल सफाई कर्मचारियों का पांचवां हिस्सा फर्जी है. उनकी तनख्वाह उठा ली जाती है और सभी कर्मचारी उसे आपस में बांट लेते हैं. पटना में प्रदूषित पानी तथा कूड़े-कचरे की सफाई न होने से स्वास्थ्य संबंधी कई गंभीर समस्याएं उभर आई हैं. डॉ. ठाकुर का कहना है कि पटना का हर तीसरा आदमी किसी न किसी तरह की पेट की बीमारी से परेशान है.

इसके अलावा प्रायः सभी शहरों में स्वायत्त संस्थाओं का बाहुल्य भी उलझन को और बढ़ा देता है. मसलन दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण, नगर निगम, विद्युत प्रदाय संस्थान, परिवहन निगम तथा खुद दिल्ली प्रशासन के बीच कोई सामंजस्य नहीं है. स्थिति इतनी खराब है कि उत्तरी दिल्ली की कई सड़कों की मरम्मत का काम तीन अलग-अलग संस्थाएं —दिल्ली विकास प्राधिकरण, नगर निगम और केंद्रीय निर्माण मंत्रालय—एक साथ देखती हैं. नगर निगम सड़क बना देता है तो टेलीफोन विभाग केबल डालने के लिए उसकी खुदाई करने लगता है. एक पूर्व पार्षद डॉ. एस.सी. वत्स कहते हैं, "दिल्ली की हालत द्रौपदी जैसी है. उसके तो सिर्फ पांच ही पति थे, दिल्ली के कई हैं." दिल्ली प्रशासन ने अब एक आयोग बैठाया है जो अन्य मामलों के अलावा इस पर भी गौर करेगा कि दिल्ली में स्वायत्त संस्थाओं के घालमेल को कैसे दूर किया जाए.

पर असलियत यह है कि सरकारें खुद ही इस घालमेल को बढ़ावा देती है. शहरों के लिए बनाए गए बड़े-बड़े मास्टर प्लान ताक पर धरकर जहां-तहां निर्माण की अनुमति दे दी जाती है. दरअसल सभी शहरों में ऊंची बहुमंजिली इमारतों की मनमानी मंजूरी दे दी गई है. दिल्ली में कनॉट प्लेस जैसे पहले से ही घने इलाके के पीछे जीवन बीमा निगम की बहुमंजिली भीमकाय इमारत बन गई है. मद्रास में पिछले तीन सालों में पुरानी इमारतों को परास्त करते 3,000 बहुमंजिले भवन खड़े हो गए हैं. पटना में 7 किमी लंबे एक इलाके को हरित-पट्टी बनाने की योजना थी. पर अफसरशाहों ने इसे अपने खुद के रहने के मकान बनाकर 'अफसर पट्टी' में बदल दिया है. और किसी जमाने में खूबसूरत राजधानी रहा लखनऊ बेतरतीब और मनमानी योजनाओं के कारण नष्ट हो रहा है. कभी शामे अवध ईर्ष्या का कारण मानी जाती थी. बग्घियों में इत्र-फुलेल लगाए अमीर-उमराव लखनऊ की सड़कों पर चला करते थे. आम लोग इक्कों और तांगों पर चलते थे. लेकिन अब उनकी जगह चीखते भोंपुओं वाली बसों ने ले ली है जो शहर में हाल-हाल में उग आई बहुमंजिली इमारतों के सामने से भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर धीरे-धीरे रेंगती नजर आती हैं. कभी शांत और सुंदर लगने वाले विधानसभा मार्ग पर 10 बहुमंजिली इमारतें बन गई हैं. ये इमारतें सरकार ने मास्टर प्लान को अंगूठा दिखाकर बनवाई हैं. इसके अलावा बगैर किसी योजना के कई नई कॉलोनियां और सहकारी बस्तियों की भरमार हो गई है.

इन तमाम समस्याओं से जूझने में अक्षम नगरपालिकाओं की व्यवस्था का ढांचा टूटने के कगार पर आ पहुंचा है. मिसाल के तौर पर बंबई नगर निगम पर कुल 324 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ गया है जिसमें 278 करोड़ रुपए सरकार से लिए गए हैं. देश के शहर राष्ट्र के कमतर संसाधनों को जैसे सोखने में लगे हुए हैं. शहरों पर होने वाले खर्च का खामियाजा ग्रामीण क्षेत्रों को भुगतना पड़ रहा है जहां विकास के लिए रकम की मात्रा दिन-ब-दिन कम होती जा रही है. अकेले दिल्ली में ही 500 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं. यह राशि दिल्ली में वसूले गए करों से बहुत ज्यादा है.

नागरिक सुविधाओं पर जितना खर्च आ रहा है, उसे देखते हुए कर आश्चर्यजनक भी नहीं हैं. कलकत्ता की गौरव भूमिगत मेट्रो रेल का उदाहरण ही लें. उस पर अब प्रति किलोमीटर 50 करोड़ रुपए खर्च आ रहा है. दिल्ली में पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के बीच 36 किलोमीटर लंबी लाईट-रेल-ट्रांजिट बनाने की एक महत्वाकांक्षी योजना है. उस पर 520 करोड़ रुपए का खर्च आने की संभावना व्यक्त की जा रही है. बंगलूर में पीने के पानी की किल्लत दूर करने के लिए 240 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं. पर पानी की किल्लत दूर करने की उम्मीदें शायद धरी की धरी रह जाएं क्योंकि जब तक यह योजना पूरी होगी तब तक शहर की बढ़ती आबादी के कारण किल्लत जस की तस ही बनी रहेगी.

इस वित्तीय संकट से उबरने का एक उपाय तो यह है कि नागरिक सुविधाओं पर आने वाला ज्यादा खर्च उठाना बंद कर दिया जाए. जैसे बंगलूर में स्वायत्त प्रशासन को 1,000 लीटर पानी की सप्लाई पर आठ रुपए खर्च करने पड़ते हैं जबकि उपभोक्ता सिर्फ 1.76 रुपए ही अदा करते हैं. दिल्ली में डीटीसी को हर किलोमीटर के पीछे पांच पैसे घाटा उठाना पड़ता है क्योंकि टिकट की दरें कम हैं. जैसा कि योजना

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आयोग के सलाहकार राकेश मोहन कहते हैं, "शहरों के विकास के लिए वहीं से पैसा इकट्ठा करना चाहिए. शहरों को अगर सही सलामत रहना है तो उन्हें अपने भरोसे पर ही टिकना होगा." पर ज्यादातर शहरों की नगरपालिकाएं या नगर निगम टैक्स बढ़ाकर अगले चुनावों में पराजय का सामना नहीं करना चाहतीं. इसलिए वही हमेशा से चली आ रही बेढंगी रफ्तार चलती रहती है.

इस बीच मकानों की कमी दूर करने के लिए ठोस विचार-विमर्श होने लगा है. केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आवास नीति बनाई है जिसके तहत राज्यों की भूमिका भवन निर्माण-कर देने की सीमा से हटकर लोगों को सिर्फ सुविधाएं मुहैया करा देने की हो जाएगी. आवास और शहरी विकास निगम के अध्यक्ष एस.के. शर्मा कहते हैं, "सरकार के बनाए मकानों के बारे में कई शिकायतें मिलती हैं. विकास संस्थाओं को इस भूमिका से मुक्त कर देने से वे सिर्फ जमीन उपलब्ध कराकर लोगों को मकान बनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकेंगी." आवास निर्माण की योजनाओं में आर्थिक मदद देने के लिए 100 करोड़ रुपए की शुरुआती पूंजी से एक राष्ट्रीय आवास बैंक भी अब बनाया जा रहा है.

दूसरे, नगर निगम और नगरपालिकाएं भी शहरीकरण की त्रासदियों से छुटकारा पाने के उपाय खोजने में लगी हैं. जैसे दिल्ली में शहर की गंदगी यमुना में डालने के बजाय उसे नहरों के जरिये पड़ोसी राज्यों के खेतों तक पहुंचाने की योजना पर विचार हो रहा है क्योंकि गंदगी और कीचड़ बेहतर उर्वरक का काम देते हैं. इसके अलावा दिल्ली में हर रोज निकलने वाला टनों कूड़ा अब भट्ठियों में जलाकर उससे ऊर्जा पैदा की जाएगी और इस ऊर्जा से बिजली की टरबाइनें चलाई जाएंगी. हालांकि कूड़े के जरिये पैदा हुई बिजली से जलने वाले बल्बों से दुर्गंध तो नहीं आएगी लेकिन नगर निगम आयुक्त पी.पी. चौहान एक और समस्या का जिक्र करते हैं, "मुश्किल तो यह है कि ज्यादातर लोग अपने यहां का कूड़ा फेंकने के लिए दो कदम दूर भी नहीं जाना चाहते. यह कूड़ा इकट्ठा करने में हमारा बहुत-सा कीमती वक्त खराब हो जाता है."

इसी बीच एनसीयू ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि बंबई मद्रास और कलकत्ता को राष्ट्रीय शहर घोषित कर दिया जाए ताकि उन्हें कोष के लिए स्थानीय निकायों की मर्जी पर निर्भर न रहना पड़े. राजधानी दिल्ली और उपरोक्त शहर देश के शहरी आर्थिक विकास के केंद्र बन गए हैं.

मसलन, देश की ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों का पांचवां हिस्सा और उनके कुल कामगारों का दस प्रतिशत बंबई में है. मोटर वाहनों के टायर-ट्यूबों का तिहाई हिस्सा कलकत्ता की फैक्ट्रियों में बनता है, और इतने ही माल डिब्बे, जूट और इस्पात की चादरें भी. लेकिन नियोजकों के सामने एक विरोधाभास भरी चुनौती है: इन शहरों में किसी भी तरह की चरमराहट जहां विध्वंसक होगी, वहीं अगर उनमें नवीकरण के लिए और पैसा लगाया जाए तो और भी बाहरी लोग वहां खिंचे आएंगे.

दिन-ब-दिन बढ़ते कूड़े के ढेरः नाकारा होती नगरपालिकाएं

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

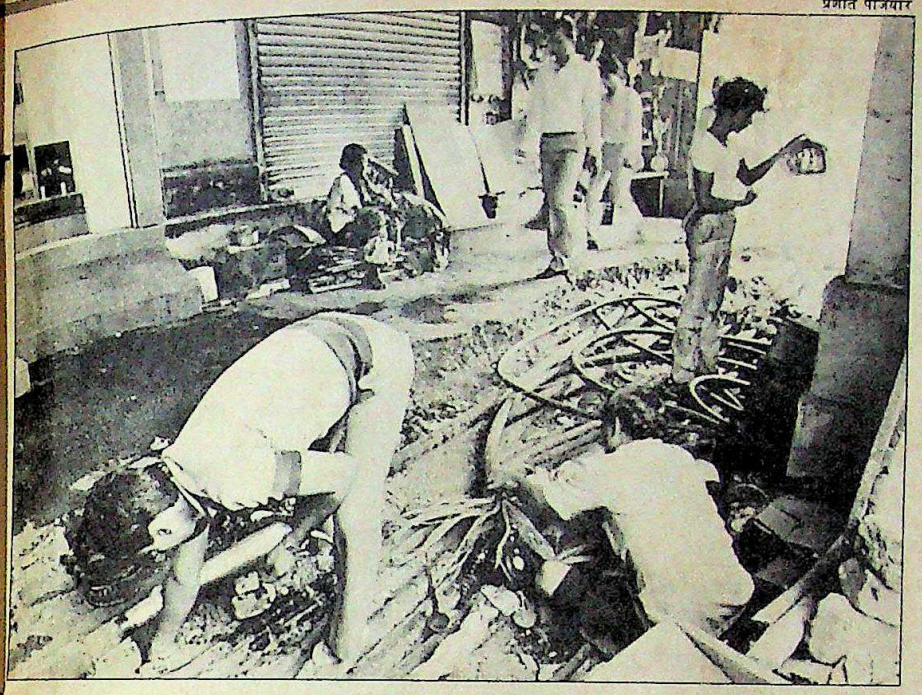
प्रशांत पंजियार

टेलीफोन के केबल डालने के लिए सड़क की खुदाई: समन्वय का अभाव

लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा तो यह है कि शहर जिस तेजी से गंदी बस्तियां बनते जा रहे हैं उस पर रोक कैसे लगाई जाए और मौजूदा गंदी बस्तियों का क्या किया जाए. उन पर बुलडोजर फिराकर वहां के लोगों को शहरों के बाहर बसाने—जैसा कि दिल्ली में इमर्जेंसी के दौर में किया गया था—का संजय गांधीनुमा समाधान आज शायद कारगर न हो. 1981 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अब्दुल रहमान अंतुले ने बंबई के डी मेलो रोड के फुटपाथों पर से झुग्गी-झोंपड़ियों को हटाने का अभियान छेड़ा था. मामला सुप्रीम कोर्ट में गया. अदालत ने नाजायज कब्जे हटाने के सरकार के अधिकार को मान्यता तो दी पर यह भी कहा कि वह लोगों को वैकल्पिक जगह मुहैया कराए.

झुग्गीवासियों को शहर के बाहरी इलाकों में जमीन और मकान देकर बसाने की दूसरी योजनाएं भी खटाई में पड़ी हुई हैं. गुजरात में झुग्गियां हटाने के लिए बनी संस्था गुजरात स्लम क्लियरेंस बोर्ड ने 5000 झुग्गीवासियों को सरखेज इलाके में साबरमती नदी के किनारे मकान आबंटित किए. पर जब झुग्गी-वासियों ने पाया कि उन्हें शहर में अपने रोजगार की जगहों तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है तो उन्होंने अपने नए मकान बेच दिए और और फिर पुरानी जगहों पर आकर जम गए.

शहरों में झुग्गियों के जंगल से निजात पाने का दूसरा विकल्प यह है कि उन्हें जहां के तहां रहने दिया जाए और मूलभूत नागरिक सुविधाएं मुहैया कराकर उनमें रहन-सहन का स्तर सुधारा जाए. लगता है यह विकल्प सही लगने लगा है तभी ज्यादातर शहरों में अब इसी को लागू करने पर विचार किया जा रहा है. इस दिशा में सबसे साहसिक कदम 1984 में मध्य प्रदेश सरकार ने उठाया. उसने सरकारी और नगरपालिकाओं की जमीन पर कब्जा जमाए बैठे लोगों को वह जमीन पट्टे पर दे दी. नतीजतन, राज्य के 48 शहरों में झुग्गियों में रहने वाले 2.62 लाख परिवार अब अपनी झुग्गियों के मालिक हो गए हैं.

पर गांवों से शहरों की ओर पलायन तथा शहरों में खाली जगहों पर जबरन कब्जे की बुनियादी समस्या बनी ही रहती है. प्रसिद्ध वास्तुकार और एनसीयू के अध्यक्ष चार्ल्स कोरिया कहते हैं, "मुख्य समस्या गांवों से शहरों में हो रहा पलायन रोकने के लिए कस्बों में तेज रफ्तार से रोजगार के मौके मुहैया कराने की है. गरीबों के लिए मुख्य मुद्दा जीवन बसर करना है, किसी तरह दो जून की रोटी मिलती रहे यही शायद उनकी प्राथमिकता होती है. घर तो उनके लिए दूसरे नंबर की चीज है. शहरों में भी काम मिलना और काम की जगह पर आसानी से पहुंचना उनकी मुख्य चिंता रहती है."

केंद्र सरकार को भी छठी योजना में आकर ही इस वास्तविकता पर ध्यान देने का समय मिला. उसने तेजी से बढ़ रहे 235 शहरों को विकसित करने के लिए चुना. यह काम तो पहाड़ जितना बड़ा था लेकिन पैसे रखे गए राई बराबर. पांच वर्षों के लिए कुल 70 करोड़ रुपए रखे गए, अर्थात हर शहर के हिस्से प्रतिवर्ष सिर्फ 60 हजार रुपए. सातवीं योजना में कुछ ज्यादा बुद्धिमानी दिखाई गई. अब सिर्फ 102 शहरों को चुना गया है और उनके लिए 88 करोड़ रुपए रखे गए हैं.

लेकिन शहरी विकास की योजना बनाने वालों के लिए सबसे पवित्र शब्द है 'क्षेत्रीय योजना'. उद्देश्य है—बड़े शहरों की ओर हो रहा पलायन मोड़ने के लिए दूसरे केंद्र विकसित करना. लेकिन दिल्ली के इर्दगिर्द राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाने की योजना भी संकट में पड़ी है. इस योजना पर 800 करोड़ रुपए खर्च होने थे लेकिन केंद्र सरकार ने सिर्फ 35 करोड़ रुपए खर्च की मंजूरी दी.

सरकारी उपेक्षा के बावजूद अधिकांश योजना बनाने वालों का मानना है कि छोटे शहरों और कस्बों को विकसित करके ही आने वाले संकट को टाला जा सकता है. बुच कहते हैं, "हमें छोटे शहरों और कस्बों में दीर्घकालिक रोजगार के अवसर बनाने चाहिए. अगर उनका विकास होता है तो दो चीजें होंगी—एक तो यह कि शहरी क्षेत्र का समान विकास होगा और दूसरा, बड़े शहरों पर पड़ने वाले पलायन के दबाव में कमी आएगी."

शहरों की 40 फीसदी औसत विकास दर से अधिक तेजी से फैलने वाले छोटे शहरों की संख्या 555 है. शहरी विकास की योजना में गड़बड़ी के बावजूद यह बात उम्मीद जगाती है. इन शहरों का विकास इतनी तेजी से क्यों हुआ और क्या ये बड़े शहरों को जाने वाली भीड़ को अपनी ओर खींच सकते हैं, इसका विस्तृत अध्ययन करने की जरूरत है. केंद्र सरकार ने अब एनसीयू को शहरी समस्या के बुनियादी कारणों का पता लगाने के लिए कहा है. संभवतः इसकी रिपोर्ट मार्च तक मिल जाएगी.

इसी बीच कलकत्ता में रहने वाले सरकारी अधिकारी प्रदीप मुखर्जी ने सुबह टहलने जाना बंद कर दिया है. वे कहते हैं, "कोई टहलने चैन के लिए जाता है, न कि थकने और तनाव बढ़ाने. अब कोई खाली जगह नहीं है जहां चैन से टहला जा सके. कंक्रीट के जंगल उगने के साथ ही शहर भी सिमट गया है और गाड़ियों का धुंआ हरदम अंधेरा किए रहता है." कुल मिलाकर फिलहाल भारतीय शहरों पर बरबादी के बादल मंडरा रहे हैं.

—राज चेंगप्पा के साथ कमलजीत रतन, फरजंद अहमद, एम.रहमान, उदय माहूरकर, नरेंद्र कुमार सिंह, श्रीधर पिल्लै, एस.एच. वेंकटरमनी और दिलीप अवस्थी की रिपोर्ट

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मध्य प्रदेश

परंपरा की व्यथाकथा

बांछड़ा जाति की बेटियां वेश्यावृत्ति करने को मजबूर

पश्चिमी मध्य प्रदेश की बांछड़ा जाति में यह प्रथा है कि परिवार की सबसे बड़ी लड़की वेश्या बनकर दूसरे सदस्यों का निर्वाह करती है. हालांकि उसे समाज की बदनामी नहीं झेलनी पड़ती पर अपनी ही जाति में विवाह करने के अधिकार से वह वंचित हो जाती है. फरवरी 1983 में विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर सरकार से इस सामाजिक कुरीति का उन्मूलन करने के लिए विशेष उपाय करने को कहा था. प्रमुख संवाददाता ***नरेंद्र कुमार सिंह*** *ने मंदसौर और रतलाम जिलों में बसी इस जाति के लोगों के बीच जाकर पाया कि बदलते दौर में भी उनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया है. उनकी रिपोर्ट :*

झोंपड़ी की छत से लटकते साधारण-से बल्ब की धुंधली रोशनी में परिवार के लोगों ने अभी खाना शुरू ही किया है. मां, बाप, भाई, बहनें, भावजें और बच्चे मक्के की रोटी और साग का भोजन करने फर्श पर बैठते हैं. गांव के हर सुखी परिवार में ऐसा ही होता है. अचानक बाहर घर्र-घर्र करता एक ट्रक रुकता है. ड्राइवर उतरकर झोंपड़ी में चला आता है. एक लड़की फटाफट भोजन से निवृत्त होकर लड़खड़ाते ड्राइवर के संग बगल वाले कमरे में चल देती है और दरवाजा बंद कर लेती है. परिवार के दूसरे लोग निर्विघ्न खाने में लगे रहते हैं. जैसे कुछ हुआ ही न हो.

यह परिवार की सबसे बड़ी बेटी है. पश्चिमी मध्य प्रदेश की बांछड़ा जाति की ऐसी ही दूसरी बेटियों की तरह वह संसार के सबसे पुराने पेशे में लगी है. लेकिन 'खिलावड़ी' (जो क्रीड़ा करे) के नाम से जानी जाने वाली ये लड़कियां वेश्यालयों में नहीं रहतीं और खुद को आम वेश्याओं से श्रेष्ठ मानती हैं. अभी-अभी 19वें साल में प्रवेश करने वाली शांति कहती है, "हम वेश्याएं नहीं हैं. कज्जाओं (ग्राहकों) को हम रिझाती नहीं हैं." वास्तव में वे परिवार की 'भत्तावड़ियों' (विवाहित महिलाओं) के साथ एक ही घर में रहती हैं. लेकिन ग्राहकों के मनोरंजन के लिए अमूमन उन्हें एक अलग कमरा दे दिया जाता है.

वास्तव में इस जाति (कुल आबादी 5,000) में वेश्यावृत्ति को सामाजिक स्वीकृति हासिल है. जाति की हर पांचवीं औरत खिलावड़ी है. पर इन औरतों को इज्जत दी जाती है. और संयुक्त परिवारों में तो उनकी हैसियत प्रायः मर्दों से भी ज्यादा मजबूत होती है. उन पर कोई सामाजिक या सांस्कारिक प्रतिबंध नहीं हैं. वे अपने परिवारों के साथ रक्षाबंधन जैसे त्यौहारों में शामिल रहती हैं. खिलावड़ियों पर बस एक ही बंदिश है कि वे अपनी जाति के मर्दों से शादी नहीं कर सकतीं.

इस कुरीति के अध्ययन के लिए बनी सरकारी समिति के अध्यक्ष रह चुके हरिजन नेता सखाराम देवकरण पटेल भी बताते हैं, "इनमें जिस्मफरोशी को न तो अपमानजनक माना जाता है और न ही घृणित. इसलिए खिलावड़ियों को परिवार और जाति की ओर से इज्जत और प्यार मिलता है." यह कुप्रथा इस कदर जड़ जमा चुकी है कि अपेक्षतया शिक्षित और खाते-पीते परिवार भी अपनी सबसे बड़ी बेटियों को इस धंधे में लगाना गलत नहीं मानते. गरीब परिवारों में तो छोटी बहनें भी पेशा करने लगती हैं.

आश्चर्य नहीं कि बेटी का पैदा होना इन लोगों में शुभ माना जाता है. अधिकांश बाप अपनी बेटियों को 13-14 साल की में रजस्वला होते ही वेश्यावृत्ति के उतार देते हैं. नथ उतराई की रस्म यहां बतौर सामाजिक उत्सव मनाया है. शराब के दौर चलते हैं और गुलछर्रे जाते हैं. इसका सारा खर्च प्रथम ग्राहक देना होता है. दाम लड़की की आयु सौंदर्य पर निर्भर होता है. 25

बांछड़ों में वेश्या को सामाजिक कलंक नहीं माना जाता. बल्कि कुछ परिवारों में उनका रुतबा पुरुषों से बेहतर होता है

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ग्राहक ट्रक ड्राइवर; (दाएं) रेखा और (बाएं) कमला

रेखा को याद है कि "मुझे 2,000 रुपए मिले थे."

नथ उतराई के बाद खिलावड़ियां जीविका कमाने के लिए अमूमन छिटपुट कज्ज़ाओं पर निर्भर रहती हैं. कज्जा आते-जाते रहें, इसके लिए ये लोग या तो बड़े गांवों के करीब पुरवों में बस जाते हैं या फिर मुख्य सड़कों के किनारे ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां ट्रक ड्राइवर रुकते हैं. नीमच-रतलाम राजमार्ग पर उनके घरों के सामने दिन में किसी भी समय ट्रक रुके देखे जा सकते हैं. बेहतर रंग-रूप वाली कुछ औरतों के बंधे-बंधाए अमीर ग्राहक भी हैं जो उन्हें हर महीने पैसा देते हैं. उनकी आमदनी पांच से लेकर 75 रुपए रोजाना तक है. छह साल से इस धंधे में लगी 20 वर्षीय निशा कहती है, "मैं आम तौर पर बैठने (संभोग) के दस रुपए लेती हूं, पर कई बार कोई अमीर कज्जा कई-कई दिन ठहर जाता है. खूब शराब-मांस उड़ाता है. ऐसे लोग बड़े-बड़े तोहफे भी दे जाते हैं." लेकिन खिलावड़ियां अमूमन गरीब होती हैं. एक सरकारी सर्वेक्षण के मुताबिक उनकी औसत आमदनी 200 रुपए माहवार है.

आम तौर पर गरीबी ही महिला को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करती है. पर कई खाते-पीते परिवार भी अपनी लड़कियों से धंधा करवाते हैं

हालांकि खिलावड़ियां पारिवारिक माहौल में सुरक्षित रहती हैं पर उनके धंधे को दूसरे सामाजिक दुष्कर्मों से भी जोड़ा जाता है. इस जाति के औरत-मर्द शराब के शौकीन माने जाते हैं. बहुत से युवक नामी अपराधी हैं जो खड़ी फसलों की चोरी करते हैं या चोरी का माल बेचने का धंधा करते हैं. मंदसौर के नगर निरीक्षक कहते हैं, "अपराधियों के अड्डे होने के कारण हम बांछड़ा गांवों पर कड़ी नजर रखते हैं. अपराध करने के बाद वे वहां मौज-मस्ती करने जाते हैं."

गुजराती, राजस्थानी और मालवी की मिली-जुली बोली बोलने वाले बांछड़ा जाति के लोग कभी घोषित अपराधी हुआ करते थे. अब मध्य प्रदेश में उन्हें हरिजन माना जाता है. लेकिन दूसरी हरिजन जातियों की तरह उन्हें न तो अछूत और न ही सामाजिक दृष्टि से नीचा समझा जाता है. पर वे कहां से आए और कैसे उन्होंने अपने विशेष रस्मो-रिवाज अख्तियार किए, इसका अभी पता नहीं चल पाया है. एक मत के अनुसार वे राजस्थान में खानाबदोश थे जिन्हें अंग्रेजों ने नीमच की अपनी छावनी में फौजियों के मनोरंजन के लिए मंदसौर जिले में ला बसाया था. मगर इस जाति के बारे में जानकारी रखने वाले एक स्थानीय अध्यापक डॉ. पूरन सहगल के मुताबिक बांछड़ा लोग मुख्य तौर पर खेतिहर मजदूर और किसान हुआ करते थे. उन्होंने देहात के अपने सामंती आकाओं के मनोरंजन के लिए यह पेशा अपनाया.

वे कहीं से भी आए हों पर उनके रस्मो-रिवाज कड़े सामाजिक नियमों में बंधे हैं. कोई भी बांछड़ा युवक किसी खिलावड़ी से हम-बिस्तर नहीं हो सकता. इसका उल्लंघन करने पर पंचायत उसका सामाजिक बहिष्कार कर सकती है और साथ में कोई भी कड़ा दंड दे सकती है. इसी तरह खिलावड़ी अपनी जाति के किसी युवक के साथ शादी रचाने का अधिकार हमेशा के लिए खो बैठती है, हालांकि पंचायत की अनुमति से वह जाति से

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

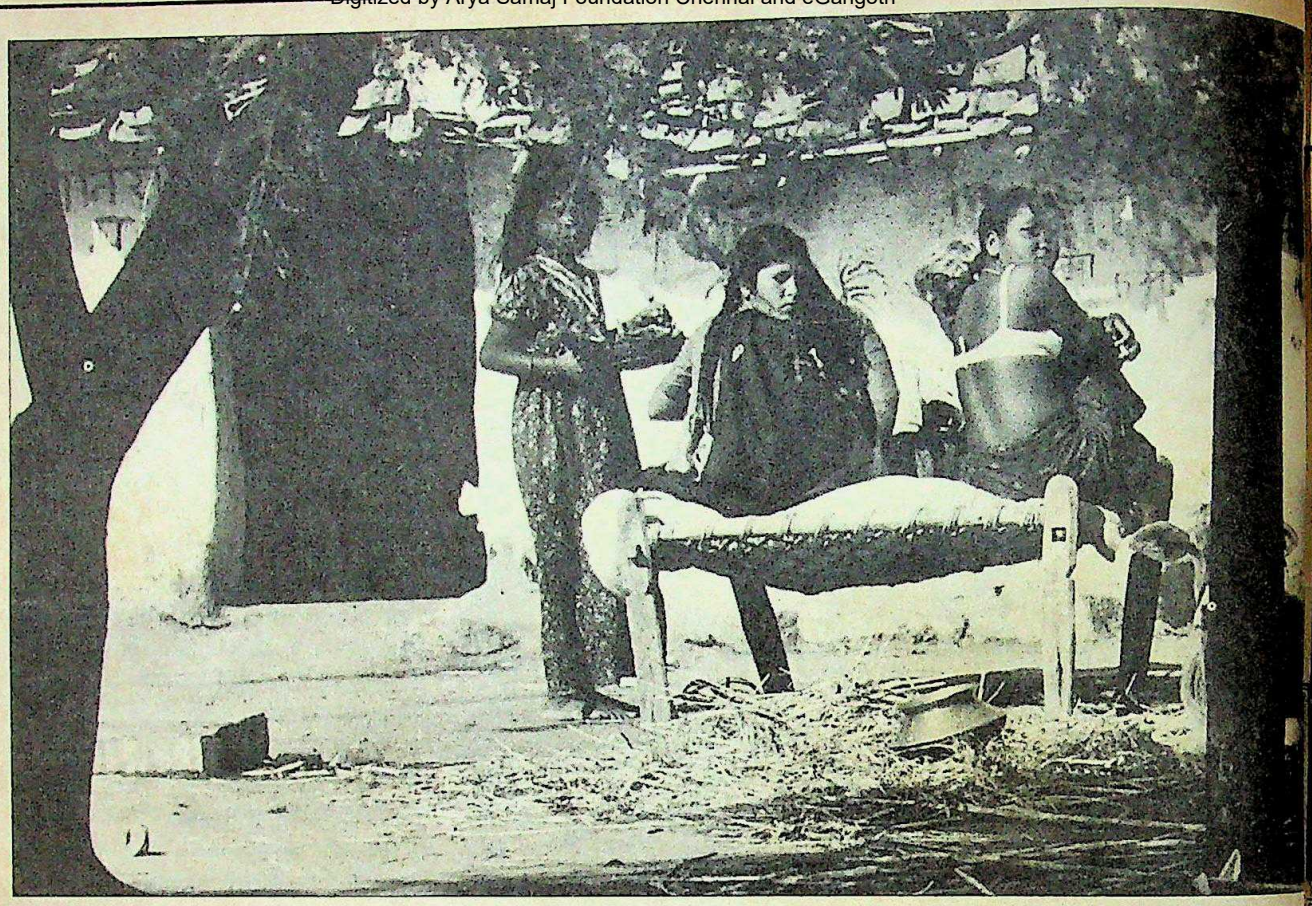

(ऊपर) ग्राहकों का इंतजार; और (बाएं) चं

बाहर शादी कर सकती है. भत्तावड़ियां किसी भी हालत में वेश्यावृत्ति नहीं कर सकतीं और उन्हें अपने खाविंदों के प्रति वफादार रहना होता है. सहगल बताते हैं, "जिस औरत पर व्यभिचार का आरोप लगता है उसे अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए खौलते तेल में हाथ डालने को कहा जाता है."

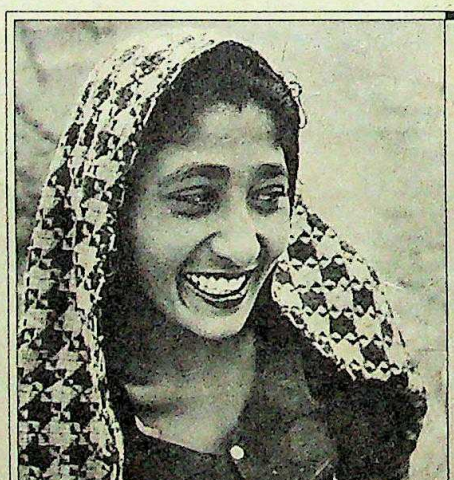

लड़की का पैदा होना शुभ माना जाता है. वधू के दाम अधिक होने के कारण बेटी को अक्सर बेटे से बेहतर माना जाता है

वेश्यावृत्ति की इस प्रथा से इस जाति की महिलाओं की हैसियत जरा भी नहीं गिरी है. इस बात की पुष्टि दुल्हन की अत्यधिक कीमत से होती है. किसी बांछड़ा युवक को अपने होने वाले ससुरालियों को 25,000 रुपए तक अदा करने पड़ते हैं. पिछले साल मंदसौर जिले में काढी गांव के बीए अंतिम वर्ष के एक छात्र रूपचंद आर्य को 20,000 रुपए बतौर दुल्हन की कीमत के देने पड़े. आर्य कहते भी हैं, "बहुत-सी वेश्याएं तो अपने बेटों की शादी के लिए जिंदगी भर की कमाई खर्च कर देने में नहीं हिचकिचातीं."

दरअसल खिलावड़ियों को बेऔलाद रहने के नाम से भी चिढ़ है. 20 साल की राधा अपने चार वर्षीय पुत्र अशोक को दुलारते हुए सवाल उठाती है, "मेरी जवानी चुक जाने के बाद कौन मेरी देखभाल करेगा?" उसकी तमन्ना है कि बेटा पढ़-लिखकर सरकारी नौकरी करे. शादी के बाद पैदा हुए अधिकांश बच्चों को उनकी मां के नाम पर जाना जाता है. लड़कियों को लड़कों पर तरजीह दी जाती है. खिलावड़ियों के पुनर्वास में सहायता देने वाले एक स्थानीय व्यापारी विष्णु वैरागी बताते हैं, "अनेक बांछड़ा गर्भवती महिलाएं तो दुआ करती हैं कि उनकी कोख से एक सुंदर-सी कन्या जन्म जिसे वे वेश्यावृत्ति के धंधे डाल सकें."

बांछड़ा महिलाएं मुख्य गरीबी के कारण ही वे वृत्ति अपनाने पर मज होती हैं. जैसे कि 18 व शांति कहती है, "हम कर भी क्या सकती हमारे पिता खेत मजदूर उनकी मृत्यु के बाद ह परिवार में दो छोटे भाई रह गए थे. उ पालन-पोषण कौन करता?" उसकी दो भी खिलावड़ी हैं. पर कई महिलाएं अपने बाप के प्रति कर्तव्य भावना में डूबकर अख्तियार करती हैं. 14 साल से वेश्या कर रही 30 वर्षीया सुनीता कहती है, अपने मां-बाप को सहारा देने से कैसे करूं? मैं ही उनकी सबसे बड़ी बेटी हूं फिर हमारी जाति में तो शुरु से यही चली आ रही है."

पर कुछ अपेक्षाकृत खाते-पीते परिवार हैं जिन्होंने इस प्रथा को नहीं छोड़

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

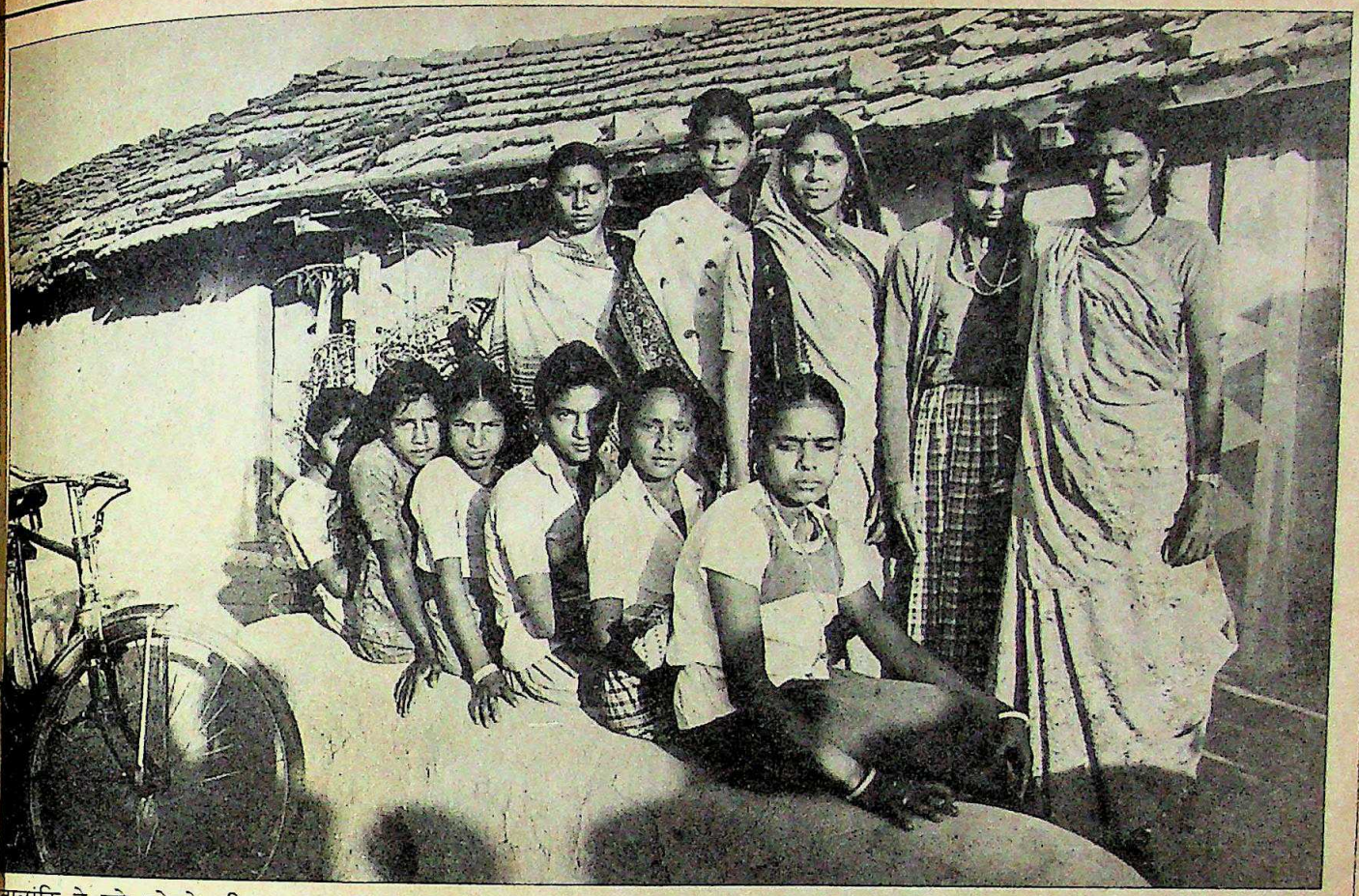

बांछड़ा वेश्याओं का पुनर्वास होस्टल; और (बाएं) राधा

जहां इस समाज के कल्याण के प्रति सरकारी रवैया अनमना-सा है वहीं सामाजिक उत्साह भी लगभग नहीं के बराबर है

हालांकि वे इसे छोड़ने की स्थिति में हैं. मसलन परवलिया के उप-सरपंच की दो बेटियां वेश्यावृत्ति करती हैं. रेखा भी कई साल से खिलावड़ी का जीवन बसर कर रही है. उसके पिता 30 बीघा के मालिक हैं जिसमें एक तिहाई सिंचित भूमि है. मंदसौर जिले के नीलकंठपुर गांव में उनका एक बड़ा मकान भी है.

यौन शोषण की अनुमति देने वाले समाज में फंसी कुछ खिलावड़ियां तो अपनी जीवन पद्धति से ऊब चुकी हैं. रेखा कहती है, "यह तो नरक से भी बदतर है. इसे कोई जिंदगी कहते हैं? जब मुझे अजनबियों के साथ सोना पड़ता है तो मेरा दिल फफक उठता है." अपनी जाति से बाहर के लड़के से शादी करने की उसकी इच्छा भी दूर का सपना बन गई है. वह दुखी होकर कहती है, "अब मुझसे शादी भी कौन करेगा?" उसकी रिश्ते की बहन 15 वर्षीय कमला को भी ऐसी जिंदगी से नफरत है. "कई बार तो मुझे शराबियों की खातिरदारी करनी पड़ती है." अनेक खिलावड़ियां यह धंधा छोड़ना चाहती हैं पर उनके पास रोजी-रोटी का कोई दूसरा साधन नहीं. न तो समाज ने और न ही सरकार ने उन्हें दूसरा कोई साधन उपलब्ध कराने की कोई कोशिश की है. मसलन 20 वर्षीया चंदा कहती है कि जिस दिन "सरकार मुझे खेती के लिए कुछ जमीन दे देगी, मैं यह धंधा छोड़ दूंगी."

मगर इस कुरीति का उन्मूलन करने के बहुप्रचारित इरादों के बावजूद राज्य सरकार ने इस दिशा में कुछ नहीं किया है. अभी तक वह इन महिलाओं के पुनर्वास के लिए केवल एक सिलाई केंद्र खोल पाई है जिसके साथ दो बोर्डिंग स्कूल जुड़े हैं. इसके अलावा सरकार किसी बांछड़ा कन्या के साथ शादी करने वाले व्यक्ति को इनाम देकर प्रोत्साहित भी करती है.

लेकिन ये तमाम सरकारी कोशिशें आधी-अधूरी ही सिद्ध हुई हैं. उनसे इन हतभागिनियों का कुछ बन भी नहीं पाया है. दोनों स्कूलों में मात्र 30 लड़कियां हैं जबकि सिलाई केंद्र 12 महिलाओं को ही सिलाई आदि का प्रशिक्षण दे पाया है. दरअसल बराड़िया गांव के बोर्डिंग स्कूल में रह रही लड़कियों में से आधी अभी भी वेश्यावृत्ति कर रही हैं. एक गांववासी का कहना है, "वे कक्षा के बाद शाम को घर लौटती हैं और फिर ग्राहकों का मनोरंजन करती हैं." 'पतित' बाछड़ा महिलाओं के लिए हकीकत तो यह है कि सरकार और उनकी अपनी ही जाति उन्हें उनके दर्दनाक अंजाम पर छोड़ चुकी है.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

परमवीर

विदेश ने कराई पहचान

पाश्चात्य संगीत को भारत में लोकप्रिय करने की अनोखी धुन

पियानो को हाथ लगाते ही परमवीर में मानो किसी दैवी शक्ति का संचार हो जाता है. संगीत ही अब उनका जीवन है. कुछ माह पहले एक स्कूल के लिए संगीत कार्यक्रम तैयार करते समय परमवीर दीन-दुनिया को ही भुला बैठे थे. उनकी मां खुर्शीद बताती हैं कि किस प्रकार परमवीर दिन भर रचनाएं तैयार करते और रात को सेंट जेवियर स्कूल में उनका अभ्यास करते.

परमवीर अपनी किस्म के अलग ही संगीतकार हैं. वे पाश्चात्य संगीत को भारत में लोकप्रिय बनाने के लिए जी-तोड़ मेहनत कर रहे हैं. उनके कॉलेज के सहपाठी सिद्धार्थ बसु बताते हैं. "परमवीर शुरू से ही प्रतिभाशाली थे." पर इस 35 वर्षीय संगीतकार को अपनी प्रतिभा के सम्मान के लिए दूसरे देशों का ही का मुंह जोहना पड़ा है.

1984 में इनलैक्स समूह (इंग्लैंड) ने उन्हें संगीत सीखने के लिए छात्रवृत्ति दी. सिर्फ दो वर्षों के भीतर ही उन्होंने टिपेट, बेंजामिन ब्रिट्टन तथा कुसीना इंटरनेशनल जैसे सम्माननीय संगीत पुरस्कार जीतकर अपने चयन को सार्थक कर दिया. उनकी संगीत रचनाओं का प्रदर्शन जेनेवा और बोस्टन में भी हुआ है.

उनकी नवीनतम संगीत रचना 'कृष्णा' न तो पूर्वी और पश्चिमी संगीत की खिचड़ी है और न ही उसमें रागों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है. वे भी इसे अपनी श्रेष्ठतम रचना मानते हैं. 'कृष्णा' बच्चों के लिए तैयार की गई श्रीकृष्ण के बाल्यकाल की साहसिक गाथा है.

सिख पिता और पारसी मां की संतान परमवीर का बचपन पुरानी दिल्ली में तबलों की थाप और उस्तादों की महफिल के बीच बीता. उनकी मां भी भारतीय शास्त्रीय गायन में माहिर हैं. नौ वर्ष की उम्र में परमवीर ने संगीत सीखना आरंभ किया और चौदह तक पहुंचते-पहुंचते वे संगीतकार बनने की ठान चुके थे.

एकांतप्रिय परमवीर ने एमए (दर्शन शास्त्र) की पढ़ाई बीच में छोड़कर फोटोग्राफी शुरू कर दी. कई वर्षों बाद वे अपने पुराने स्कूल सेंट जेवियर्स में संगीत शिक्षक की नौकरी करने लगे. यहां उन्होंने 'ग्ली क्लब' की स्थापना की और संगीत थिएटर में कई नए प्रयोग भी किए.

परमवीर अपने एक शिष्य के साथ

छात्रों को वे पाश्चात्य संगीत सीखने के लिए प्रोत्साहित जरूर करते थे लेकिन इसकी निराशाजनक स्थिति से भी भली-भांति परिचित हैं. "इस संगीत साधना की मुझे भारी कीमत चुकानी पड़ी है. लोगों को इस संगीत के जरिये मिलने वाले सम्मान ही दिखाई देते हैं, उनके पीछे छिपा वर्षों का संघर्ष नहीं," वे बताते हैं.

अब तक अविवाहित परमवीर कई संगीत प्रतिभाओं को निखार चुके हैं. उनके पांच शिष्य अल्पकालिक छात्रवृत्ति पर लंदन जा चुके हैं. इस वर्ष उनके 17 वर्षीय शिष्य नागभूषण को संगीत अध्ययन के लिए इनलैक्स छात्रवृत्ति मिली है.

'70 के दशक में पहली बार संगीत की दुनिया में परमवीर का नाम चर्चित हुआ. उन्हीं दिनों उन्होंने न्यूयॉर्क में एक संगीत कार्यक्रम 'रनअवेस' देखा जिससे वे इतने भाव-विह्वल हुए कि तालियां तक बजाना भूल गए. वहां से लौटने के बाद कुछ 'खास' कर दिखाने के लिए उन्होंने एक 'संगीत थिएटर वर्कशॉप' शुरू किया. यह एक अनूठा प्रयोग था जिसमें बच्चे हर रविवार को वहां बैठकर राजनीतिकों, स्कूलों, माता-पिताओं और फिल्मों के बारे में अपने विचार, ड्रम बजाते हुए लय में प्रकट करते. इन्हीं के आधार पर उन्होंने कई मौलिक और प्रभावी संगीत रचनाएं तैयार कीं. वे कहते हैं "मैं जानता हूं कि इस देश में लाखों लोग भूख से मरते हैं. मैं बच्चों को आसपास के वातावरण के प्रति संवेदनशील बनाना चाहता हूं." उनकी पहली संगीत रचना 'किड-स्टफ' थी. यह कुछ बच्चों की जीवनियों पर आधारित थी, और काफी चर्चित हुई थी.

ब्रिटेन के अग्रणी संगीतज्ञ पीटर मैक्सवेल डेविस ने जब ये संगीत रचनाएं सुनीं तो वे बहुत प्रभावित हुए. उन्होंने इनलैक्स से परमवीर के नाम की सिफारिश की कि उन्हें प्रतिभाशाली संगीतज्ञ ऑलिवर नूसेन के साथ संगीत अध्ययन के लिए इंग्लैंड बुलाया जाए. इस तरह इंग्लैंड ने उन्हें वह सम्मान दिया, जो भारतवासी नहीं दे पाए थे.

परमवीर के व्यक्तित्व के दो पहलू हैं—एक सफल संगीतज्ञ का, जो इंग्लैंड के एक छोटे-से फ्लैट में अपना पियानो साथ रखकर सोता है, दूसरा वतन से दूर एकाकी व्यक्ति का जो अपने देश लौटने को व्यग्र है. परमवीर मानते हैं कि उनके मन में भारी द्वंद्व चल रहा है. "संगीत की सफलता के लिए मुझे इंग्लैंड में रहना पड़ेगा, लेकिन यहां मेरे पास पैसों की भारी कमी है. और दोस्त भी ज्यादा नहीं हैं. इसी कारण मैं अपने संगीत में भारत को शामिल करना चाहता हूं."

परमवीर के अलावा दो ही भारतीयों ने पाश्चात्य संगीत में नाम कमाया है—जुबीन मेहता और एडिनबर्ग के नरेश सोहल. दोनों तो विदेश में ही बस गए है, लेकिन परमवीर को उम्मीद है कि भारत से उनके रिश्ते हमेशा बने रहेंगे. —सिमरन भारद्वाज

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हमेशा से पहली पसंद

हर घर में, घर घर में, घर घ

घर में, घर घर में, घर घर मे

घर घर में, घर घर में, घर

घर में घर घर

में, घ र में, घ

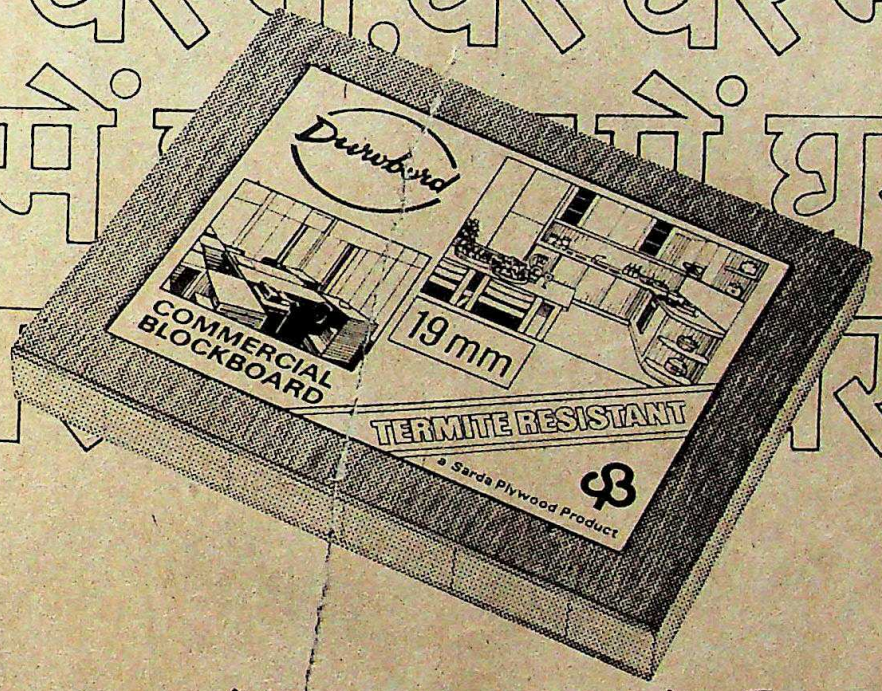

यह है ड्यूरो – ब्लॉकबोर्ड का हीरो

शत-प्रतिशत की टाणु अवरोधक. मौसम परिवर्तन से अप्रभावित. गुणवत्ता, जो बीस से अधिक वर्षों से विश्वसनीय है. – अपनी कीमत का सही दावेदार. यही वजह है कि समझदार लोग हमेशा ड्यूरोबोर्ड ही लेना पसंद करते है. पूरे परिवार का भरोसेमंद. हर घर में... घर घर में...

सारदा प्लाइवुड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड

जैपुर (असम)

मुख्य विक्रय कार्यालय - १/७, डी. बी. गुप्ता रोड, नई दिल्ली ११००५५

DPS/SPI-877

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

छाया लेख: रघु राय

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

युद्धकलाएं

लहराते जिस्मों की जांबाज़ी

संगीत की स्वर लहरियां, एकदम नपी-तुली कलाबाजियां और हैरतनाक अंग व शस्त्र संचालन—दर्शकों को अभिभूत कर देने के लिए इतना काफी था. मणिपुर की 'थंग-टा' हो या चीन की 'ताई-ची-चुआन'—युद्धकलाएं शारीरिक-आत्मिक क्षमता के विकास का जरिया ही नहीं, बल्कि युद्धक मनोविज्ञान की मूर्त दस्तावेज हैं. प्रस्तुत है हाल में कलकत्ता में संपन्न हुए नाटक, नृत्य व युद्धकलाओं के एशियाई उत्सव पर रघु राय के चित्र और कमलजीत रतन का आलेख:

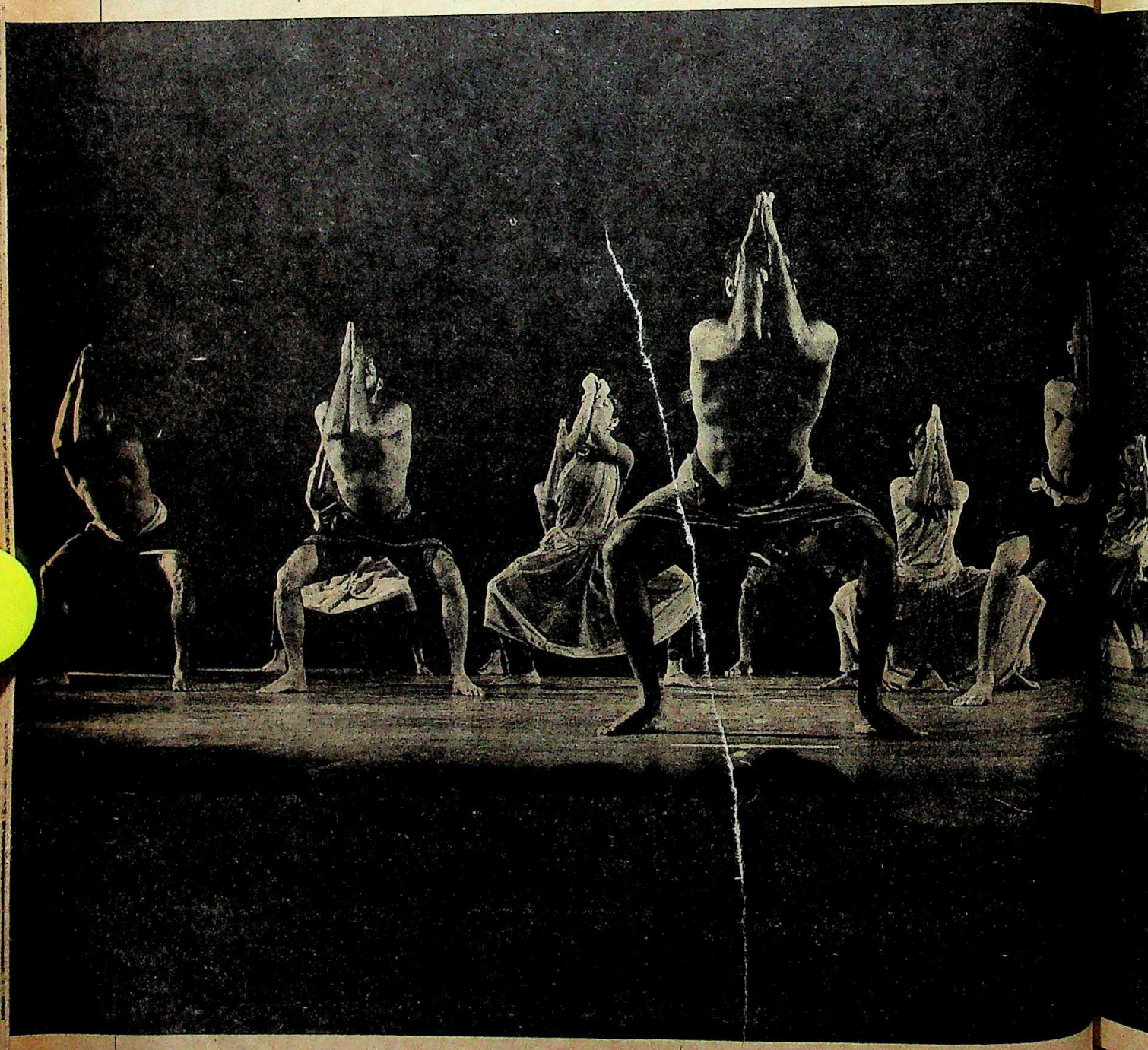

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जिस्मों का लचीलापन और पेशियों की क्रियाशीलता देखकर अवाक रह जाना पड़ा. हाल ही में कलकत्ता के दर्शकों को 25 देशों से आए कलाकारों द्वारा प्रदर्शित कुछ असामान्य प्रदर्शन देखने का मौका मिला. इन प्रदर्शनों में विलक्षण नृत्य, दिखावटी लड़ाइयां तथा एकल प्रदर्शन शामिल थे. ये कलाकार नाटक, नृत्य तथा युद्धकलाओं के एशियाई उत्सव में हिस्सा लेने सप्ताह भर के लिए शहर में थे. उत्सव के साथ ही एक महत्वपूर्ण परिसंवाद और कार्यशाला का भी आयोजन किया गया था. ऐसा निराला कार्यक्रम इससे पहले दुनिया में कहीं भी नहीं हुआ. इस उत्सव का मकसद परंपरागत तथा सामयिक युद्धकलाओं और मंचीय कलाओं के बीच अंतर्संबंध खोजना था.

उत्सव का आयोजन मंचीय कला से संबंधित एक संस्था 'पदातिके' ने भारतीय नाट्य संघ तथा यूनेस्को की अंतरराष्ट्रीय नाटक संस्था के साथ मिलकर किया. इसमें दिखाई गई भारतीय कलाओं में मणिपुर, असम, तमिलनाडु, केरल तथा मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में प्रचलित युद्धकलाएं भी थीं. डेनमार्क के 'ओडिन थिएटर' के निदेशक 51 वर्षीय यूजिनो बार्बा ने कहा, "यूरोपीय देशों के लोगों में भारतीय कलाओं के प्रति काफी आकर्षण है. इसका मुख्य कारण इनसे जुड़ी धार्मिक भावनाएं हैं. पश्चिम में स्थिति इसके उलट है, जबकि भारत में धर्म, नाटक और युद्धकलाएं एक ही परंपरा का हिस्सा हैं."

उत्सव में शाम के वक्त कलाओं का मंचन होता तथा दूसरे दिन सुबह संगोष्ठियों तथा कार्यशालाओं में उन पर चर्चा होती थी.

पेइचिंग ऑपेरा द्वारा चीनी युद्धकला ताई-ची-चुआन के प्रदर्शन के साथ उत्सव की शुरुआत हुई. व्यायाम की इस पद्धति को ताओसी मठ ने विकसित किया है. इसका मुख्य उद्देश्य प्रतिकूल परिस्थितियों में संघर्ष नहीं बल्कि अपना बचाव करना है.

11वीं सदी के चीन के राजवंश सूंग के एक दार्शनिक चांग-सन-फेंग ने एक बार एक पक्षी और एक सांप को लड़ते देखा. पक्षी तेजी से चोट कर रहा था पर सांप की चकमेबाजी के कारण उसके प्रहार निष्फल हो जाते थे. सांप जिस तरीके से पक्षी से अपना बचाव कर रहा था उसे देख चांग काफी प्रभावित हुए. सांप के इस बचाव को लड़ाई जीतना नहीं कहा जा सकता, तो इसे लड़ाई हारना भी नहीं कहा जा सकता. उन्होंने ताई-ची-चुआन युद्धकला इसी सिद्धांत के अनुरूप विकसित की. इसमें शरीर की 108 क्रियाओं वाली व्यायामों की एक लंबी पद्धति है. इससे शरीर की पेशियों पर अद्भुत नियंत्रण, संतुलन बनाने की अपूर्व क्षमता का और शारीरिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का विकास होता है.

लेकिन दर्शकों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया एक भारतीय युद्धकला ने. यह थी मणिपुर की युद्धकला थंग-टा. दूसरे दिन कार्यशाला में बहुत से लोग इसे सीखने की इच्छा जाहिर कर रहे थे. इस पारंपरिक व्यायाम में कई शस्त्रों का भी प्रयोग होता है जिनमें थंग (तलवार) और टा (भाला) प्रमुख हैं. माना जाता है कि तलवार राक्षसी प्रवृत्तियों को परे रखती है जबकि भाला रक्षक की भूमिका निभाता है.

थंग-टा में नर्तक बहुत नपे-तुले ढंग से कलाबाजियां खाता है. इसके मुख्यतः तीन चरण हैं. ये पूरी कला में सुबह, दोपहर और संध्या का प्रतिनिधित्व करते हैं. जैसे-जैसे इस युद्धकला का विकास होता गया वैसे-वैसे इसमें नफासत भी आती गई. इसे देख कर दर्शक प्रफुल्लित हो उठते हैं.

मणिपुर की विशुद्ध शास्त्रीय युद्धकला

'अंगिका' : काबिले तारीफ; और (दाएं) इलियाना : नया प्रयोग

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

संकीर्तन भी थंग-टा से प्रभावित है. लेकिन संकीर्तन युद्धकला का अधिक परिष्कृत रूप है. इसका प्रदर्शन यज्ञोपवीत, शादी तथा श्राद्ध जैसे प्रायः सभी सामाजिक कार्यकलापों के अवसर पर किया जाता है. नट-संकीर्तन में नृत्य, प्रहसन तथा पाठ के तत्व तो मिले ही हुए हैं, इस अवसर पर ढोलक और करताल भी बजाया जाता है.

दूसरी भारतीय कला, जिसने दर्शकों को प्रभावित किया, केरल की थी. यह युद्धकला कलारीपयतु उतनी ही पुरानी है जितना यह राज्य. केरल के बारे में मान्यता है कि भगवान परशुराम ने अरब सागर से इसका उद्धार किया था. इसके दौरान कलाकारों के सुगठित काले शरीर जब पसीने से तर-बतर हो जाते हैं तब उनकी आभा देखकर लगता है मानो वे शक्ति के मूर्त रूप हों. इसे देखकर यह जानना आसान हो जाता है कि सदियों के बाद भी यह कला लोगों की स्मृति में इतनी क्यों छाई हुई है.

यह युद्धकला सिर्फ लड़ाई के ही काम नहीं आती बल्कि यह शरीर और मन को अनुशासित करने की एक विधि भी है. आज भी कलारीपयतु की तालीम पारंपरिक शैली के अखाड़े में किसी गुरु के निर्देशन में होती

कलारीपयतु में शरीर ही शस्त्र है. इस शरीर पूरी तरह संवेदनशील और सचेत हो जाता है. पूरा शरीर जैसे आंखों में बदल जाता है. इसका मतलब यह भी है कि आप साथ ही आप सांसारिक तथा भावजगत प्रति सचेत हो जाते हैं. इसलिए जहां कला लड़ाई में सहायक सिद्ध होती है, वहीं कलाकार के शरीर और मन दोनों को पवित्र करती है. असल में कलारीपयतु कलाकार शरीर के हर अंग के बारे में इस बारीकी से जानता होता है कि वह

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट बन जाता है.

पूर्वी भारत की लोकप्रिय युद्धकला 'छाऊ' के कलाकार बिहार के सरायकेला, ओडीसा के मयूरभंज तथा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से आए थे. छाऊ नृत्य के कलाकारों को विशेष व्यायाम सीखना पड़ता है तथा कलाबाजियों और लंबी छलांग में पारंगत होना पड़ता है. छाऊ नृत्य के साथ बजने वाला संगीत भी युद्ध संगीत ही होता है. रंगबिरंगी पोशाक तथा मुखौटे इस नृत्य का आकर्षण बढ़ाते हैं.

छाऊ नृत्य के कलाकारों में स्थानीय शैलियों तथा परंपराओं की सीमा से ऊपर उठकर आने वाले दो कलाकार थे—इलियाना सिटारिस्टिक और भरत शर्मा. मयूरभंज इलाके की छाऊ शैली में इन दोनों कलाकारों ने यूनानी मिथक 'इको ऐंड नार्सीसस' का मंचन किया, जिससे उनकी अपूर्व क्षमता का पता चलता है.

इस मिथक में इको जंगल में शिकार खेलने आए नार्सीसस से प्यार करने लगती है. नार्सीसस पहले तो उसकी तरफ खिंचता है पर बाद में उसे त्याग देता है. इस दुख से वह सूखकर कांटा हो जाती है. सिर्फ वाणी ही शेष रह जाती है उसकी. तब घमंडी और निष्ठुर नार्सीसस को सभी वनदेवियां शाप देती हैं कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार करने लगेगा जिसे वह कभी पा नहीं सकेगा. इस शाप के वश वह पानी में अपनी तस्वीर देखकर उसी से प्यार करने लगता है. और परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो जाती है. ध्वनि-प्रकाश वाले इस प्रदर्शन में इलियाना अपनी भूमिका में पूरी तरह खरी उतरी और उसका अभिनय पूरे उत्सव में सबसे अच्छा रहा और दर्शकों को बांधे रखा.

इंडोनेशिया की युद्धकला 'पेनकाक सिलाट' ने भी दर्शकों का ध्यान खींचा. हाथ से लड़ने की विधा पर आधारित इस नृत्य में किसानों के दैनिक जीवन को मूर्त रूप दिया गया है. नृत्यकलाओं में धनी पश्चिम सुमात्रा का मीनांगकबाऊ इसका स्रोत-स्थल है. सिलाट की पारंपरिक शिक्षा किसी मस्जिद के करीब बने अखाड़े में दी जाती है. इसमें निपुणता तथा लगन की बहुत जरूरत पड़ती है. इस कला का अनोखा पहलू है कलाकार को दैनिक जीवन की गतिविधियों में जादुई तेजी प्रदान कर देना.

सामयिक मंचीय कलाओं में चंद्रलेखा की 'अंगिका' को प्रशंसा मिली. 'अंगिका' काम करने की पारंपरिक शैली युद्ध-कला, योग तथा नृत्य का मिलाजुला रूप थी.

हालांकि यह उत्सव बहुत ऊंचे स्तर का था, फिर भी इसमें स्थानीय लोग नहीं जुटे. इसके अधिकांश दर्शन या तो इसमें हिस्सा लेने वाले थे या फिर इसके आयोजक और उनके परिवारजन. कुछ सुविख्यात लोग जैसे—फिल्म निर्देशक मृणाल सेन और नाट्य निर्देशक सत्यदेव दुबे इसमें यह जानने के लिए आए कि युद्धकलाओं का उपयोग मंच के कलाकारों के लिए कितना सहायक सिद्ध हो सकता है. 'पदातिक' के एक निदेशक श्यामानंद जालान ने कहा कि युद्धकला सिर्फ शरीर को चुस्त करने या लड़ाई में काम आने वाली कला ही नहीं है. उन्होंने बताया कि चूंकि अभिनय में शरीर, वाणी और मन सबकी भूमिका है इसलिए अभिनेताओं को युद्धकला में प्रशिक्षण से बहुत सहायता मिलेगी.

इसमें संदेह नहीं कि इस उत्सव से युद्धकलाओं के अध्ययन और परंपरागत तथा सामयिक कला रूपों पर उसके असर को परखने में सहायता मिलेगी.

मयूरमंज का छाऊ नृत्य (बाएं) और चीनी शैली का नृत्य (दाएं): कलाबाजी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कविता संग्रह

बर्फीले ताप की अनुभूति

सर्जनात्मकता का आनंद देती हैं आचार्य की कविताएं

शब्द भूले हुए
कविता संग्रह
नंदकिशोर आचार्य
पूर्वा प्रकाशन मंदिर, बीकानेर
कीमत : 36 रुपए

कवि में एक गहरा संवेदनात्मक ताप है, जीवंत स्मृति, रचना की सामर्थ्य है और शब्दों से ममत्व है, पर साथ ही पूरे संग्रह को पढ़ते हुए बार-बार यही प्रश्न रह-रहकर उमड़ता है कि आखिर इतना धीमा क्यों है यह ताप? वे कौन-से दबाव हैं जो इसे तेजस्विता और प्रकाश तक पहुंचने नहीं देते. ये कविताएं ऊष्मा का एहसास देती हैं, पर तेजस् से नहीं भरतीं. क्या समकालीन हिंदी पाठकों को मात्र ऊष्मा के एहसास की अपेक्षा है अपने प्रिय कविजनों से? क्या इतनी ऊष्मा— संवेदन की भी और बोध की भी— स्वयं प्रत्येक सामाजिक में ही जाग्रत नहीं होती? तो क्या कविता को सामाजिक की भावना और बौद्धिकता की अनुकृति या अनुकीर्तन ही होना चाहिए? अथवा आत्मोत्कर्ष का पथ—संकेत भी? ये प्रश्न इस ताप के धीमेपन की अनुभूति के सहवर्ती हैं.

अपने ताप के धीमेपन से स्वयं कवि सुपरिचित हैं. पहली ही कविता— 'नये क्रम में'— वे सीधे कहते भी हैं, 'फूंक से जगाता हूं आग/सोयी हुई/एक धीमा ताप/सब पर व्याप/जाता है, मीठा और उदास.' यह तब है, जब 'बर्फ बाहर गिर रही है' पर वह बर्फ क्या है? कविता संग्रह में इसके पर्याप्त साक्ष्य हैं. उस बर्फ के गिरने की स्थिति में कवि अपनी फूंक से जिस आग को जगाता है वह आग एक मीठा, उदास, धीमा ताप देती है यानी यह आग भी बर्फीली ही है. वह एक बर्फीला ताप ही देती है. न दहक, न धधक, न चमक. बस सिर्फ एक कसक.

संग्रह के तीन हिस्से या जैसे अध्याय हैं—(1) पकने लगा है हरा, (2) राग मरुगंधा, (3) खोई हुई दुनिया में. अंतिम खंड 'खोई हुई दुनिया में' पढ़ते हुए इस गिर रही बर्फ की अधिक वैविध्यपूर्ण झलक मिलती है. ये कविताएं जैसलमेर के पुराने शहर और आसपास की खंडहर बस्तियों से प्रेरित हैं. इनमें 'ठिठकती, कुछ फुसफुसाती स्मृतियां हैं' जिनसे पुष्ट होता है कि 'अभी जीवित है यह शहर.' खंडहरों के विविध खंडों का मार्मिक उत्कीर्णन है इन कविताओं में. कवि देखता है कि 'गलियों में से निकल रही गलियों में से जातीं गलियों में आतीं संकरे मुंह गलियां' 'अंदर से फैली रागिनियों' सी हैं, जो 'इस नगर के महाराग में घुलती' थीं, पर वे अब 'लुप्त स्वर' हैं. स्वरों, लयों, तानों, रागिनियों और उस पूरे महाराग का यह विलोप ही वस्तुतः बर्फ का गिरना है. पर यह विलोप क्यों हो रहा है? कवि का धीमा ताप हमें इस जिज्ञासा के प्रकाश तक नहीं ले जा पाता.

'फूंक से जगाता हूं आग सोयी हुई; एक धीमा ताप सब पर व्याप जाता है मीठा और उदास'
नंदकिशोर आचार्य
'नए क्रम में'

कवि कहते तो यही हैं कि ये 'जालीदार झरोखे', 'चाहे खंडित हों' पर ये 'एक निरंतर रचना हैं', जो 'मुझमें पूरी होती बारंबार'. वे यह भी कहते हैं कि 'देवता मानो अब भी वहीं कहीं बसते' हैं और यह भी कि 'याद देवता है, मंदिर भी'. पर उन देवताओं, मंदिरों और रचनाओं की वर्तमान क्रियाशीलता का कोई संकेत या साक्ष्य या झलक इस कविता संग्रह में कहीं नहीं है. कहां हैं देवता नये रूपों में? कहां हैं नए मंदिर? कहां हैं वे रचनाएं निरंतर सर्जनशील नवरूपों में? और यदि हैं, तो फिर बर्फ का गिरना भी एक अलग तरह के आलोक का ही झरना है, बरसना है. और फूंक से जगायी जा रही आग से कौंधते आलोक में उस झर रहे आलोक का बोध दिपना चाहिए, जैसा कि निराला और प्रसाद की अनेक रचनाओं में दिपता है और जैसा कि अज्ञेय ने अपनी विविध रचनाओं में व्यक्त किया है. ऐसी बोध-दीप्ति आचार्य के काव्य में अभी नहीं आ पाई है. फलतः उनकी कविताएं कहीं तो बोध के एक प्रचलित स्तर की ही अभिव्यंजना करती हैं और कहीं सहसा एक उत्कृष्ट स्तर की. लगता है कि जिन पंक्तियों में एक बहुआयामी व्यंजना दिखती है, वे पारंपरिक अनुभूति की स्मृति की पंक्तियां हैं, उस अनुभूति की सिद्धता अभी नहीं आ पाई है.

फिर भी आचार्य का कवित्व वैसी सिद्धता की अपेक्षाएं जगाता है, यह कम महत्वपूर्ण नहीं. विशेषकर ऐसे दौर में जब वास्तविक जीवन में वीरता के नितांत अभाव की पूर्ति कविताओं से करने के चक्कर में वागाडंबर का मलबा ही रचना कहकर प्रस्तुत किया जा रहा हो, आचार्य की कविताएं अपनी सर्जनात्मकता का आनंद देती हैं. संग्रह की प्रेम कविताएं भी रसात्मक हैं. 'पिता के न रहने पर' कविता गहरा प्रभाव छोड़ती है. 'राग मरुगंधा' खंड में मरुथल के जीवंत बिंब हैं, पर 'रेगिस्तान की सूखती देह' की 'गहरे कुंए-सी आत्मा' का 'तले में देर तक थिरकता जल' कवि के अनुसार 'प्रेम की स्मृति की सिहरन' है. बस! स्मृति से (या में) सिहरता प्रेम क्यों नहीं है वह?

एक अखंड बोध-प्रतिमा का सर्जन ही कविता का सर्जन है. अपने इस संग्रह में आचार्य यह आशा उकसाते हैं कि वे अखंड बोध-प्रतिमा रचेंगे. पर फिर एक अधूरेपन तक ही ले जा पाते हैं. यह अधूरापन संग्रह की रसात्मक प्रेम कविताओं में से अनेक में भी है. एक ओर 'चौमासा' जैसी सशक्त कविता है. दूसरी ओर 'बर्फ सात-सी आओगी' है जिसमें कवि स्त्री को सूखी घास-सा और 'उसे' बरसात कहता है और गलने-घुलने को आतुर. बिना किसी संकेत के कि इस प्रक्रिया में नवांकुरण, नवरचना संभव होगी. 'भूले शब्द की तरह' में यह कहना कि 'तुम्हें छटपटाहट वह, मेरा अर्थ होगी' भी अधूरी और खंडित अभिव्यक्ति है.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कहानी संग्रह

शहरी मुखौटों की शिनाख्त

व्यवस्था और समाज की कुरूपताओं का सुंदर चित्रण

श्रवण कुमार की चुनी हुई कहानियां—2
कहानी संग्रह
विनीत प्रकाशन, दिल्ली—110091
पृष्ठ—104, कीमत—30 रुपए

लगभग आधा दर्जन कथा संग्रहों के लेखक श्रवण कुमार का ताजा संग्रह 'श्रवण कुमार की चुनी हुई बारह कहानियां (भाग-2)' शहरी जीवन से सीधे साक्षात्कार कराता है और 'लालफीताशाही' व 'वर्ग व्यवस्था' से पनपी बुराइयों के मुखौटे एक-एक कर उतारता है.

लेकिन इनमें से ज्यादातर कहानियां पहले से चर्चित होने मात्र से चयन की दृष्टि से किसी भी तरह किताब में जगह पाने की हकदार नहीं बन जातीं. पिछले बीस सालों के दरम्यान लिखी गई इन कहानियों में से संग्रह की सात कहानियां ('सलाख पर घूमता आदमी', 'बवंडर', 'जंगल', 'चेहरे', 'भिखमंगे', 'नहीं, यह कोई कहानी नहीं' और 'डायन') निश्चय ही पत्र-पत्रिकाओं तक ही सीमित रहतीं तो बेहतर था.

बहरहाल, इसी संग्रह की 'विरोध', 'कहकहे', 'खंडहर', 'मामूली लोग', और 'धब्बा' कहानियां ही संग्रहणीय जान पड़ती हैं जो लेखक की पिछले दस सालों (1966 से 1976 तक) की बेहतर तक्काशी और प्रौढ़ रचनाधर्मिता की मिसाल भी हैं.

'विरोध' कहानी में सरकारी मशीनरी और व्यक्ति की अस्मिता को कल-पुर्जे में बदलने वाली या उसे खारिज कर देने वाली नौकरशाही का चित्रण है. कहानीकार ने व्यवस्था' के तमाम बेजा औजारों के खिलाफ खड़े कुछेक लोगों के जरिये एक अफसर का ही क्षणिक मोहभंग कराया है. कहानीकार व्यवस्था से उसे मिले दूर-दराज पहाड़ी क्षेत्र में 'ट्रांसफर' के दंड का ही एहसास कराकर (पब्लिसिटी अफसर को) दुःस्वप्नों में भटकने के लिए क्यों छोड़ देता है? यही इस कहानी की कमजोर रग है. यथास्थिति में पात्रों को त्रिशंकु बनाकर छोड़ देना फिल्मकारों की ही नहीं, कुछेक कहानीकारों की भी बेबसी नजर आती है.

सग्रह की एक और कहानी 'कहकहे' अपनी अलग पहचान रखने वाली 'माध्यम' पत्रिका में छप चुकी है और इस संग्रह की भी सर्वाधिक चर्चायोग्य कहानी है. इस कहानी में भी एक डिप्टी डायरेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, व्यापारी और ऐसे ही सामंती चरित्रों के जरिये सुविधाभोगियों की एक पूरी जमात के मुखौटे उतारे गए हैं. ये सभी 'श्रेष्ठि जन' अपने-अपने तरीकों से हासिल शर्मनाक तजुर्बों की नुमाइश एक दूसरे के सामने बेतकल्लुफी से कहकहों का लुफ्त उठाते वक्त करते हैं और काइंयापन व निर्लज्जता का भी प्रदर्शन करते हैं.

"फिल्म शो तो फिल्म शो है. दस डाक्यूमेंट्रीज दिखाएं या एक. भाषण भी भाषण ही है, दस आदमी जुटाएं या दस हजार..."
श्रवण कुमार
कहानी 'विरोध' में

कहानी का क्लाइमेक्स इस जमात के 'विरले' श्रेष्ठि जन (मिनिस्टर) की दावत पर खर्च हुए बिल की रकम सिर्फ आठ आने बताए जाने के क्रूर मजाक से आतंकित कर देता है. कहानी के अंत में सुनाई पड़ने वाले कहकहे निश्चय ही व्यभिचारी हंसी को चीख के व्याकरण में बदलते हैं. यह कहानी समाज के सबसे अधिक भ्रष्ट और ऊंचे तबके के हिंस्र स्वभाव की सही पहचान कराती है.

'खंडहर' कहानी गरीबी से जुड़ी वेश्या-वृत्ति के उघड़ जाने और अमीरों की भोगवृत्ति के दबे-ढके रहने का फलसफा बन गई है. एक खंडहर में आने वाले जोड़ों और वहां आसपास ही होने वाले कुकर्मों को लेखक अतीत की विलासिता से भी जोड़कर देखता है. फिर सीधे उस वर्ग के दो चेहरों को सामने ले आता है जो भोग्य वस्तु के लिए कहीं भी तलछट मुंह मारने को तैयार रहता है अन्यथा छटपटाता है. वस्तुस्थिति में 'चल सकती थी' कहकर खिसकने की मुद्रा भी अपनाता है. या फिर खुमारी चढ़ने पर आधी हिंदी और आधी अंग्रेजी में जनक्रांति का दर्शन बघारता है—यही है वह बिचला और बुद्धिजीवी वर्ग.

एक और कहानी है—'मामूली लोग' जिसमें रिफ्यूजी लोगों की जिंदगी का एक्सरे उतारा गया है. मारकाट (1947) के दिनों के निगेटिव इस कहानी में उभारे गए हैं और बताया गया है कि सांप्रदायिकता के कितने धब्बे इन लोगों के रेटिना (आंखों) में क्यों और कैसे उतर आए हैं.

मारकाट-1947 की त्रासदी पाकिस्तान से दरबदर हुए कई हिंदी, उर्दू लेखकों ने पूरी तल्खी के साथ रची है. हिंदी में इस पर अज्ञेय ('बदला' कहानी) और भीष्म साहनी ('तमस' उपन्यास) बेजोड़ लिख चुके हैं. 'धब्बा' में सवर्णों के पिछड़ेपन पर चोट है.

बाकी कहानियों में भी सच तक पहुंचने की कोशिश तो नजर आती है लेकिन साथ ही कहानी के शीर्षक पर खरा उतरने की जल्दबाजी भी. इतना भर काफी नहीं है. 'सलाख पर घूमता आदमी' और 'भिखमंगे' ऐसे ही प्रयोगों के उदाहरण है जिन्हें मानव मन की प्रयोगशाला में या किसी दफ्तर में बैठे-बैठे 'बढ़ती मुद्रास्फीति' की चपेट में आए दो वर्गों के परीक्षण के लिए हर दस साल बाद लिख दिया जाता है. सुभाष पंत से लेकर ब्रजेश्वर मदान तक ऐसे ही प्रयोग अपनी-अपनी क्षमता के हिसाब से करते रहते हैं. श्रवण कुमार में निश्चय ही बेहतर संभावनाएं हैं. इसलिए उन जैसे गंभीर कथाकार को 'बबुआ पाठकों' को ही निगाह में रखकर कहानी का जुगराफिया तैयार नहीं करना चाहिए. गलत सरोकारों से जूझने और फैसले पर पहुंचने वाले, बल्कि अपनी जिजीविषा बचाने का दमखम रखने वाले लोग भी इसी समाज में रहते हैं. क्या कहानीकार कभी उनके भीतरी संसार में प्रवेश कर अनुभवों से संपन्न नहीं होना चाहेगा?

—प्रताप 'पारखी'

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इंसाफ की पुकार

वही बासी लटके

मारधाड़ की परंपरा कायम

'मैं ने कोई खून नहीं किया, मैंने...', चीखता हुआ एक कैदी युवक बदहवास-सा इधर से उधर भाग रहा है. दूसरे ही दिन उसे फांसी होने वाली है. इसी जेल में अमीरों के दुश्मन और गरीबों के मददगार दो दोस्त भी बंद हैं. उनकी हमदर्दी पाकर युवक बताता है कि किस तरह उसकी बहन का अपहरण हुआ और उसके साथ बलात्कार करने के बाद उसे मार डाला गया. और फिर जब वह कानून के रक्षकों की मदद और इंसाफ पाने के लिए भाग-दौड़ रहा था तो उलटे उसे ही एक टैक्सी ड्राइवर के कत्ल के इलजाम में झूठमूठ फंसा दिया गया. रॉबिनहुड मार्का दोनों परोपकारी दोस्त इस बेचारे युवक की बात सुन उसे मुसीबत से बचाने की ठान लेते हैं. सबसे पहले सवाल उठता है कि उसकी फांसी कैसे रोकी जाए? फैसला तुरंत लिया जाता है. एक 'रॉबिनहुड' युवक को एक कोने में ले जाता है और चोट कर-कर के उसकी एक टांग तोड़ डालता है. जाहिर है जब तक वह स्वस्थ नहीं होता, उसे फांसी भी नहीं दी जा सकती. और तब तक असली अपराधियों को पकड़वाया जा सकता है.

'इंसाफ की पुकार' में धर्मेंद्र व जितेंद्र: परोपकार और हिंसा

यह एक प्रसंग 'इंसाफ की पुकार' के पूरे ताने-बाने का खुलासा कर देता है. ऐसी कहानी, तिस पर कई-कई खलनायक (कादर खां, शक्ति कपूर, प्रेम चोपड़ा, अनुपम खेर) और एक प्रमुख भूमिका में धर्मेंद्र—यानी हिंसा और ऐक्शन का पूरा मंच तैयार है. दोनों 'रॉबिनहुड' (धर्मेंद्र, जितेंद्र) जेल से बाहर आकर अपने नए अभियान में जुट जाते हैं.

बलात्कार और हत्या वास्तव में नंबर दो के धंधे करने वाले एक सफेदपोश व्यक्ति (प्रेम चोपड़ा) के भाई (शक्ति कपूर) ने की है, यह बात उन्हें मालूम ही थी. बस सबूत जुटाने थे. इसके लिए अपराधी सरगना (प्रेम चोपड़ा) और उसके सहयोगी पुलिस इंस्पेक्टर (कादर खां) की लड़कियां क्रमशः भानुप्रिया और अनीता राज को प्रेमजाल में फंसाने की योजना बनाई गई. तमाम फाइट सीनों, कई गीतों व गलतफहमियों के बाद यह कार्यक्रम संपन्न हुआ और रॉबिनहुड द्वय का उठाया बीड़ा अंततः सिरे लगा.

इस बीच एक के बाद एक पुराने चलताऊ फार्मूले परदे से गुजरते हैं. अचानक पता चलता है कि जिस युवक के सिर पर फांसी का फंदा लटक रहा है वह परोपकारी दोस्तों में से एक (जितेंद्र) का भाई है, यानी बलात्कार की शिकार लड़की उसकी बहन थी. यह भी कि दूसरे दोस्त (धर्मेंद्र) के माता-पिता की हत्या भी संबंधित अपराधी चौगुटे के ही एक सदस्य (अनुपम खेर) ने मास्क पहनकर की थी. इन रहस्योद्घाटनों से इस अभियान में दोनों परोपकारी दोस्तों की संलग्नता ही नहीं, उनका गुस्सा और क्रूरता भी बढ़ गई. मामला अब जाती दुश्मनी का जो बन गया था.

निर्माता रमेश ग्वालानी व राज भक्ति-यानी की 'इंसाफ की पुकार' में निर्देशन (अपने क्षेत्र के दिग्गज) टी. रामराव का है. 'अंधा कानून' जैसी सुपर हिट और 'नाचे मयूरी' व 'संसार' जैसी सोद्देश्य फिल्में देने वाले रामराव के लिए यह फिल्म कोई नई उपलब्धि लेकर नहीं आई. कम-से-कम 60 फिल्मों में निर्देशन दे चुके रामराव हालांकि मानते हैं कि, "फिल्म में दर्शकों को बांध सकने वाली कहानी के साथ-साथ हंसना-गाना-रोना सभी कुछ जरूरी है," मगर 'इंसाफ की पुकार' की कहानी जहां बस लकीर भर पीटती है, वहीं गीत-संगीत (आनंद बख्शी व लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल) भी दम तोड़ता लगता है. बेजान लटकों-झटकों से भरी एक प्रभावहीन कहानी को संवादों (शब्द कुमार) ने भी जैसे कंधा देने का ही काम किया है.

पूरे 1987 में जिस हिंसा के सहारे हिंदी फिल्मोद्योग अपनी नाव खेता रहा और धर्मेंद्र जिसकी सबसे बड़ी धुरी बने रहे उसने साल की इस अंतिम फिल्म में भी उनका पिंड नहीं छोड़ा. बीते साल की शुरुआत राजकुमार कोहली की 'इंसानियत के दुश्मन' से हुई थी, और उसमें भी धर्मेंद्र मौजूद थे. वहां भी उनका अभिनय कृत्रिम हिंसा का शिकार रहा था और वह फिल्म भी इसी की तरह बेसिर-पैर की घटनाओं से भरी पड़ी थी. 'इंसाफ की पुकार' इस बात का सबूत है कि साल भर में हिंसा व एक्शन को लेकर फिल्मकारों के ऊलजलूल सोच यात्रा विकृति के किस खतरनाक पड़ाव तक पहुंच गई संवाद अदायगी में जहां धर्मेंद्र ने अपने पंजाबी लहजे से दर्शकों को हंसाया.

और हंसाने का जिम्मा अब नायक हो या खलनायक, लगभग सभी को उठाना पड़ रहा है. खासकर कादर खां खलनायकी विधा को हास्य में रंगने की भरपूर कोशिश में जुटे लगते हैं. जितेंद्र 25 साल बाद भी जितने चुस्त नजर आते हैं उतने ही अभिनय शून्य. और जहां अभिनय के अवसर का सवाल है तो दोनों हीरोइनें ज्यादातर पृष्ठभूमि में रहती हैं. अनीता राज (जिनकी जोड़ी सनी देओल के साथ कहीं अच्छी लगती) बुढ़ाते धर्मेंद्र से लिपट कर जुगुप्सा ही पैदा करती हैं, जबकि भानुप्रिया उन लोगों का मजाक उड़ी महसूस होती हैं जिन्होंने कभी दक्षिण इस 'नई' लड़की को श्रीदेवी के सिंहासन लिए खतरा बताया था. अनुपम खेर ने महज अपनी फिल्मों की गिनती में एक का इजाफा भर ही किया. उनकी अभि प्रतिभा के मद्देनजर (टी. रामराव की 'संसार' और 'इंसाफ की पुकार' दो एक विपरीत छोर माने जा सकते हैं. का 1987 के साथ ऐसी फिल्मों का सूरज अस्त हो जाता.

—सुशील कुमार

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मज़ा आ गया

क्रिस
लाईम सोप

ताज़गी का संदेशा लिये एक नई बहार आई है ।
क्रिस लाईम सोप । नींबू की प्यारी सुगँध । मन में
उभरती हुई खुशी । क्रिस लाईम सोप से नहा कर तो देखिये ।
आप कह उठेंगे, 'मज़ा आ गया !'

नीबूं की महकती ताज़गी

A Kusum Product
विश्वास के साथ खरीदिये

K-2H-87

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शहंशाह

पर्दे पर आने में हिचक

निर्माता व वितरकों में घमासान से रिलीज में और देरी

'शहंशाह' रिलीज होने को लेकर [illegible] गड़बड़झाला हो रहा है वैसा ही इस फिल्म [illegible] निर्माण के समय भी हुआ था. टीनू आनंद [illegible] इस फिल्म के लिए अमिताभ को 1986 [illegible] साइन किया था पर बंगलूर में शूटिंग [illegible] होने के तीन दिन पहले ही हीरो महोदय [illegible]

अमिताभ बच्चन के लिए 1987 एक मायने में रिकार्ड वर्ष साबित हुआ है. पिछले आमचुनाव में इलाहाबाद से इंका के सांसद बने सुपर स्टार ने राजनीति से संन्यास लेने के बाद हालांकि 10 फिल्में साइन की पर उनकी एक भी नई फिल्म पिछले साल रिलीज नहीं हुई. निर्माता-निर्देशक टीनू आनंद की ताजातरीन फिल्म 'शहंशाह' को ही लें—प्रधानमत्री के इस प्यारे दोस्त की घटती लोकप्रियता की चर्चाओं और उनके राजनैतिक विरोधियों द्वारा फिल्म के बहिष्कार की धमकियों के मद्देनजर 'शहंशाह' अधर में लटक गए लगते हैं.

'शहंशाह' के रिलीज होने की तारीख पिछले अगस्त से दो बार टल चुकी है. इससे इन. आशंकाओं को बल मिला है कि इस फिल्म के खिलाफ कुछ राजनैतिक दलों के संगठनों की देशव्यापी आंदोलन चलाने की धमकियों से सुपर स्टार और उनके निर्माता खौफज़दा हो उठे हैं. फिल्म पहले 6 अगस्त को रिलीज होनी थी, फिर इसे 27 नवंबर तक खिसका दिया गया. अब कहा जा रहा है कि फिल्म 12 फरवरी को रिलीज होगी. पर 'शहंशाह' अगले महीने भी परदे पर आ पाएंगे या नहीं इसमें संदेह ही है. उधर दो बड़े निर्माताओं—सुभाष घई और राहुल रवेल ने अमिताभ को लेकर फिल्म बनाने का आइडिया ही ड्राप कर दिया है.

सुभाष घई तो आज भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े दो-तीन शोमैन में माने जाते हैं. सुपरहिट फिल्मों की एक लंबी शृंखला देने वाले घई की काफी समय से अमिताभ को लेकर फिल्म बनाने की इच्छा थी. मगर भारी तामझाम के साथ 'देवा' का मुहूर्त करने के कुछ ही समय बाद अचानक उन्होंने इस प्रोजेक्ट को छोड़ देने की घोषणा की. उन्होंने बार-बार कहा कि अमिताभ की राजनैतिक छवि से इस मामले का कोई संबंध नहीं, फिर भी अटकलों ने पिंड नहीं छोड़ा. फिर बायकाट की धमकियों से भी इन अटकलों को बल मिला. मगर 'शहंशाह' के निर्देशक और सह-निर्माता टीनू आनंद कहते हैं कि बायकॉट की धमकियों से वे कतई चिंतित नहीं. उनका कहना है, "मैं क्यों चिंता करूं?" साथ ही वे याद दिलाते हैं कि '70 के दशक में सत्यजित राय की फिल्म 'गोपी गाइन बाघा बाइन' का जब बहिष्कार किया गया तो वह बांग्ला की हिट फिल्म साबित हुई थी.

दूसरे कुछ फिल्म निर्माताओं और अनेक प्रेक्षकों का भी मानना है कि फिल्म के बहिष्कार की धमकी का बॉक्स ऑफिस पर कोई खास असर नहीं होगा. अमिताभ के लिए सबसे ज्यादा हिट फिल्में बनाने वाले निर्माता-निर्देशक मनमोहन देसाई कहते हैं, "अब तक तो आंदोलन की सिर्फ चर्चा ही सुन रहे हैं. लोग यदि यह फिल्म देखना चाहेंगे तो वे देखेंगे जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए." निर्माता अमित खन्ना ने कहा, "हिंदी फिल्मोद्योग में अब भी अमिताभ ही एकमात्र ऐसा अभिनेता है जिसकी साख बनी हुई है." और इस विवादास्पद अभिनेता की परदे पर लोकप्रियता का सबूत पिछले छह महीनों में रिलीज हुई उनकी अनेक पुरानी फिल्मों के नतीजों से भी मिलता है. कोई नई फिल्म रिलीज न होने के कारण. उनकी पुरानी फिल्मों के 200 प्रिंट इस वक्त देश भर के थिएटरों में चल रहे हैं और कई जगह तो ये फिल्में 'हाउस फुल' ले रही हैं. अपने चमत्कारी अभिनेता की लोकप्रियता के बारे में हिंदी फिल्म निर्माताओं को अगर कोई शुबहा रहा होगा तो वह बंबई के मिनर्वा थिएटर में पिछले कई हफ्तों से हाउस फुल चल रही 'शोले' ने अब तक दूर कर दिया होगा. यही हाल देश में विभिन्न जगह पुनः रिलीज हुई 'शराबी,' 'कालिया,' 'खून-पसीना,' 'लावारिस' आदि का रहा.

मगर इससे स्थिति पूरी तरह स्पष्ट भी नहीं होती. पुरानी हिट फिल्मों के प्रति लोगों का रुझान और बात है और करोड़ों की लागत से बनी एकदम नई फिल्म की कामयाबी दूसरी बात. इसके अलावा 'शहंशाह' के पधारने में देरी की जो एक वजह काबिले-गौर है, वह है फिल्म निर्माता कंपनी—फिल्म विज़न—और वितरकों में इस बात पर ठन जाना कि अमिताभ की नई फिल्म भी पहले की तरह धुआंधार कमाई कर सकती है.

'शहंशाह' में अमिताभः पशोपेश

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अपनी पुरानी बीमारी—पेशियो में दुर्बलता—के कारण बिस्तर से लग गए. तब तक केवल प्रत्येक टेरीटोरी (वितरण क्षेत्र) में फिल्म वितरण के अधिकार 45-45 लाख रुपए में बेचे जा चुके थे, बल्कि तीन गाने भी फिल्माए जा चुके थे और निर्माता इस पर 15 लाख रुपए खर्च भी कर चुके थे.

अमिताभ की बीमारी साल भर चली और फिर उन्हें अपनी दूसरी फिल्मों के निर्माताओं को भी तारीखें देनी पड़ीं. इस तरह 1985 के लगभग अंत में जाकर ही फिल्म की शूटिंग दुबारा शुरू हो पाई. इस दरम्यान फिल्म की हीरोइन भी बदल गई. डिंपल कपाडिया की जगह मीनाक्षी शेषाद्रि को ले लिया गया. इस तरह पिछले अक्तूबर में जाकर 2.5 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली यह फिल्म तैयार हो पाई. पर चूंकि 'शहंशाह' अभी तक सेंसर बोर्ड के सामने हाजिर नहीं हुए हैं इसलिए कानूनी तौर पर इस फिल्म को वितरकों के सुपुर्द नहीं किया जा सकता.

टीनू आनंद के साथ अमिताभ (ऊपर) और मीनाक्षी शेषाद्रिः फार्मूलेबाजी

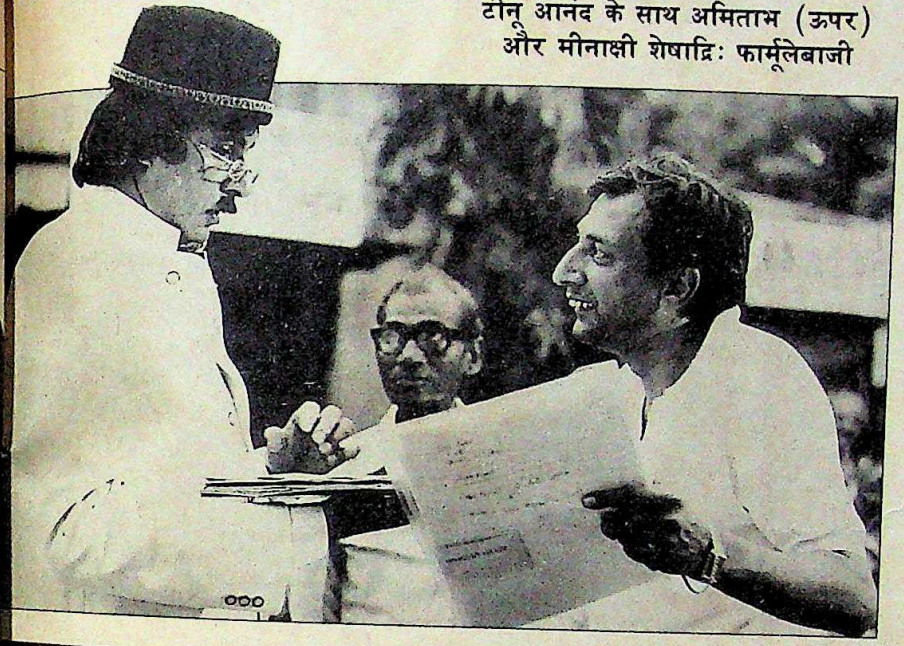

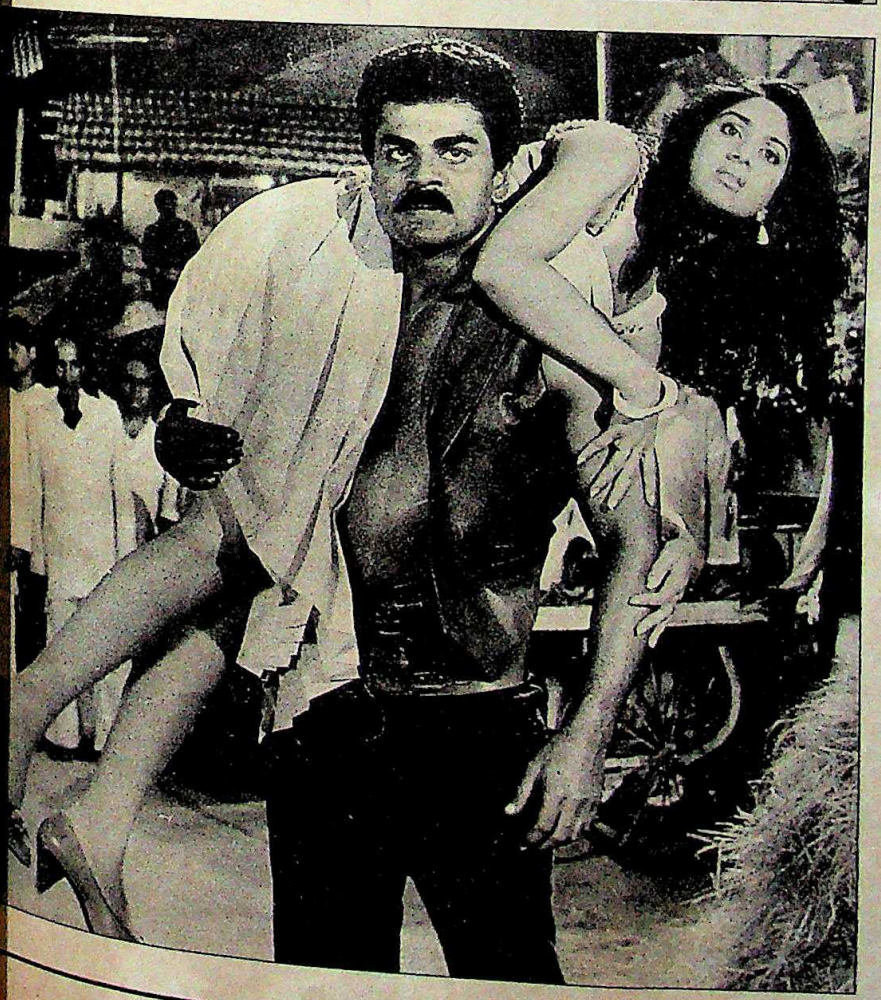

फिल्म के वितरण में देरी की एक बड़ी वजह यह भी है कि निर्माता—टीनू आनंद, उनके भाई बिट्टू और निर्माण कंपनी फिल्म विज़न के पार्टनर नरेश मल्होत्रा—अब फिल्म बिक्री की शर्त बदलने के मूड में आ गए हैं. सभी हिंदी फिल्में एक तयशुदा पद्धति के तहत बेची जाती हैं जिसे न्यूनतम गारंटी की पद्धति कहते हैं. इसमें, जब तक, यानी 10 साल बाद, फिल्म के अधिकार फिर से निर्माता को नहीं मिल जाते, तब तक वितरक और निर्माता दोनों फिल्म प्रदर्शन से होने वाली आमदनी एक फार्मूले के तहत हासिल करते रहते हैं. पर अब 'शहंशाह' के निर्माता आठ भारतीय और एक विदेशी टेरीटोरी (वितरण क्षेत्र) के वितरकों को फिल्म के अधिकार स्थायी तौर पर बेच देना चाहते हैं. इसकी वजह यह है कि अब उन्हें अपनी कंपनी—फिल्म विज़न—को भंग करके स्वतंत्र रूप से काम करना है. नतीजे में उन्होंने वितरकों के सामने प्रत्येक टेरीटोरी के लिए 'शहंशाह' को एकमुश्त 90 लाख रुपए (कथित तौर पर) में खरीद लेने का नया प्रस्ताव रखा है.

बताया जाता है कि ज्यादातर वितरक तो नया करार करने को उत्सुक हैं पर बंगाल और दिल्ली-उत्तर प्रदेश टेरीटोरी के वितरक इसके कतई पक्ष में नहीं. नतीजतन वितरकों और फिल्म के निर्माताओं के बीच घमासान मच गया है. फिल्म व्यवसाय की पत्रिकाओं में एक-दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं. टीनू आनंद ने तो हाल में यह दंभोक्ति भी कर डाली कि 'शहंशाह' के रिलीज होने के लिए वे 20 वर्षों तक भी इंतजार कर सकते हैं.

पर अमिताभ की पिछली फिल्म 'आखिरी रास्ता' के निर्माता पूर्णचंद्रराव, टीनू आनंद और वितरकों में सुलह कराने की कोशिश में लगे हैं. उन्होंने खुद भी बंबई टेरीटोरी में 'शहंशाह' के वितरण के अधिकार अमिताभ से खरीद रखे हैं. मध्यस्थता के उनके प्रयासों के चलते उम्मीद है कि अर्से से चल रहा यह झगड़ा शायद सुलझ जाए. और जहां तक सुपर स्टार का सवाल है तो 'शहंशाह' की नियति ही तय करेगी कि वे और कितने समय तक हिंदी फिल्मोद्योग के 'शहंशाह' बने रह सकते हैं.

—एम. रहमान

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तंजावुर

एक अद्भुत उपक्रम

भित्तिचित्रों को सुरक्षित रखने की नई और अनोखी विधि

तमिलनाडु के मंदिरों वाले शहर तंजावुर में पुरातत्ववेत्ता साढ़े चार साल की सख्त मेहनत के बाद ऐतिहासिक चित्रकला की परतों को अलग-अलग करने में कामयाब होते लगते हैं. इसका श्रेय इतालवी टेक्नोलॉजी को है.

इटली में भित्तिचित्रों को एक दीवार से छीलकर दूसरी पर लगाने के लिए 'डिस्टेको' पद्धति प्रयोग में लाई जाती है. तंजावुर के प्रसिद्ध मंदिर में ऊपर से गढ़ी गई चित्रकला की परतों को अलग करने में भी यही पद्धति इस्तेमाल की गई. फिर भी अलग की गई परत सुरक्षित रह गई.

यह चित्रकला तंजावुर के बृहदीश्वरर मंदिर के गर्भगृह की परिक्रमा के दोनों ओर भित्तिचित्रों के रूप में मौजूद है. इनकी दो श्रेणियां हैं. पहली श्रेणी में वे लेपचित्र हैं जो 11वीं सदी में चोल वंश के शासनकाल में चूने के गीले पलस्तर पर ही बनाए गए थे. दुनिया में सबसे ऊंची बुर्ज (12 फुट) वाले इस मंदिर का निर्माण चोल महाराजा राजराजा (प्रथम) ने करवाया था. लेपचित्रों के बारे में माना जाता है कि वे 1011 ईस्वी में मंदिर का निर्माण पूरा होने के तुरंत बाद बनाए गए थे. दूसरी श्रेणी की चित्रकला 16वीं सदी में नायक वंश के शासनकाल में पुराने लेपचित्रों पर ही 'टेंपरल' पद्धति से बनाई गई थी. दोनों भित्तिचित्रों के मध्य जोड़ के लिए गोंद का इस्तेमाल किया गया था.

चोल चित्रकला चार सदी तक नायक वंश के फ्रेस्को चित्रों के नीचे छिपी पड़ी रही. 1935 में प्रसिद्ध इतिहासकार और पुरातत्वविद प्रोफेसर के.वी. गोविंदास्वामी की अचानक ही उन पर नजर पड़ गई क्योंकि नायक चित्रकला कई एक जगहों से उखड़ गई थी.

इसके तुरंत बाद पुरातत्वविद डॉ. एस. परमस्वामी ने ऊपर से गढ़ी गई नायक चित्रकला को छीलना शुरू कर दिया.

इतिहासकार, भारतविद और तमिल के विद्वान आई. महादेवन, जो इस समय एक्सप्रेस समूह के तमिल दैनिक 'दिनमणि' के संपादक हैं, कहते हैं, "फिर पुरातत्ववेत्ताओं को सूझा कि नायक

नायक चित्रों को हटाना (नीचे) और हाल में पता लगे चोलकालीन चित्र

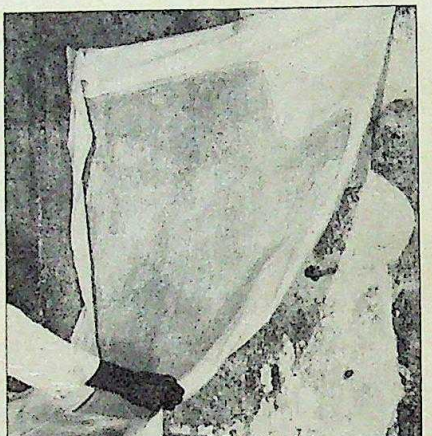

चित्रकला के नमूने भी अपने तौर पर मूल्यवान हैं और इसलिए चोल कृतियों को सामने लाने की खातिर उन्हें नष्ट नहीं किया जाना चाहिए." पहले उन्होंने नायक चित्रकला छीलने के लिए 'स्ट्रेपो' पद्धति का प्रयोग किया. इससे ऊपर से चस्पां की गई कृतियों का रंग ही उतरता था और वे नष्ट हो जाती थीं. अब पुरातत्ववेत्ताओं ने इसके बजाय संशोधित 'डिस्टेको' पद्धति को इस्तेमाल करने की सोची. इसमें ऊपर से चस्पां की गई चित्रकला को रंग सहित छीला जा सकता था. दक्षिण क्षेत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पुरातत्व रसायन अधीक्षक एम. सुब्बारमन, जो संशोधित डिस्टेको पद्धति के जन्मदाता हैं, बताते हैं, "चित्रकला की परतों को एक-दूसरे से अलग करना दीवार से चित्रकला की केवल एक ही परत को अलग करने की तुलना में बहुत ज्यादा मुश्किल है."

नई पद्धति में नायक चित्रकला पर कपड़े की दो परतें चिपकाई जाती हैं—एक जालीदार कपड़े की और दूसरी सूती कैनवस की. चिपकाने के लिए टॉलुइन और पॉलिविनाइल एसीटेट का घोल का इस्तेमाल होता है. चित्रकला पर चिपकाए कपड़े को 'फेसिंग क्लाथ' कहा जाता है. अमूमन तीन-चार दिन में 'फेसिंग क्लाथ' पूरी तरह सूख जाने पर नायक चित्रकला के किनारों पर रबड़ की नोक वाले लकड़ी के हथौड़े से छीला जाता है ताकि उसे धीरे-धीरे नीचे चोल भित्तिचित्र से अलग किया जा सके.

छीली गई नायक कलाकृति को मेज पर उलटा रखा जाता है. उसके पीछे का भाग मुलायम करके उस पर फेविकोल से मजबूत कैनवस की दो परतें चिपका दी जाती हैं. फिर कैनवस पर पॉलीयूरिथीन फोम की एक तह बिठाई जाती है. अंत में फोम पर एपॉक्सी रेजिन से फाइबर ग्लास जड़ दिया जाता है. आगे के हिस्से में कैनवस और जालीदार कपड़े के 'फेसिंग क्लाथ' को कृत्रिम विलायक पदार्थों के जरिए हटाया जाता है. फिर नायक चित्र कृति को सीधा रखकर चौखटे में सजा दिया जाता है. सुब्बारमन पिछले साढ़े चार साल से चित्रों की छिलाई में लगे हुए हैं. वे दस में से के कक्ष में 80 फीसदी काम पूरा कर चुके हैं. चार नायक चित्रों पर फाइबर ग्लास चढ़ाया गया है. प्रदर्शन के लिए मंदिर में जाएगा.

—एस.एच. वेंकटे

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

केरल

आधुनिक इलाज की आंधी

निजी अस्पताल फलते-फूलते धंधे से खूब चांदी काट रहे हैं

त्रिवेंद्रम के 67 वर्षीय अवकाशप्राप्त क्लर्क बालकृष्णन नायर— पिछले माह बायपास सर्जरी के लिए मद्रास गए लेकिन हताश ही लौटे क्योंकि मद्रास का सस्ते-से-सस्ता अस्पताल, जिसकी फीस 40,000 रुपए थी, उन्हें तीन महीने के पहले भर्ती करने को तैयार नहीं था. नायर की बेटियों ने पिता के ऑपरेशन के लिए अपने आभूषण तक बेच डाले थे. वे कहती हैं, "भगवान का लाख-लाख शुक्र है कि अब त्रिवेंद्रम में एक नया अस्पताल खुल गया है, जहां बायपास सर्जरी की फीस लगभग 30,000 रुपए ही है."

तीन वर्ष पहले इदुक्की जिले के 65 वर्षीय इलायची उत्पादक के.वी. अवराचन ने तमिलनाडु के वेल्लोर स्थित क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज से एक पेस-मेकर लगवाया था. इस ऑपरेशन के लिए उन्होंने अपनी जमीन का छोटा-सा टुकड़ा बेच डाला था. लेकिन पिछले माह पेस-मेकर में खराबी आने के कारण उन्हें कोचीन के मेडिकल ट्रस्ट अस्पताल में भर्ती होना पड़ा. हालांकि उन्हें अब 15,000 रुपए अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे. लेकिन यह उस खर्च के मुकाबले बहुत कम होगा, जो उन्हें केरल के बाहर इलाज कराने में करना पड़ता.

केरल का निम्न तथा मध्यम वर्ग सहसा ही अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत हो उठा है. उच्च तकनीकी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाने की ललक के कारण केरल में प्राइवेट अस्पताल तेजी से पनपने लगे हैं. नायर तथा अवराचन जैसे और भी कई मलयाली हैं जिन्होंने सामर्थ्य न होते हुए भी इलाज पर मोटी रकम खर्च की.

त्रिवेंद्रम के क्षेत्रीय कैंसर केंद्र के निदेशक डा. कृष्णन नायर का कहना है कि "केरल के लोगों की जीवन शैली— उच्च जीवन स्तर, लंबी आयु— के कारण हृदय, जिगर तथा गुर्दे संबंधी बीमारियों और कैंसर की संभावना बढ़ जाती है." केरल के एक प्रमुख सर्जन टी.एम. जोसफ के अनुसार, "मलयाली थोड़ी-सी तकलीफ होने पर खुद ही अस्पताल का रुख करते हैं. यहां का गरीब-से-गरीब व्यक्ति भी पूरी डॉक्टरी जांच करवाना चाहता है."

उच्च तकनीकी चिकित्सा सुविधाएं अब निजी अस्पताल मुहैया करा रहे हैं. वेल्लोर अस्पताल में 15 वर्ष काम करने और सर्जरी के सहायक प्राध्यापक पद से इस्तीफा देने वाले डॉ. जोसफ भी मानते हैं कि "सरकारी अस्पतालों में आवश्यक उपकरणों और दवाइयों का अभाव डॉक्टरों का उत्साह समाप्त कर देता है. निजी अस्पतालों में उन्हें कम-से-कम काम करने का संतोष तो मिल ही जाता है."

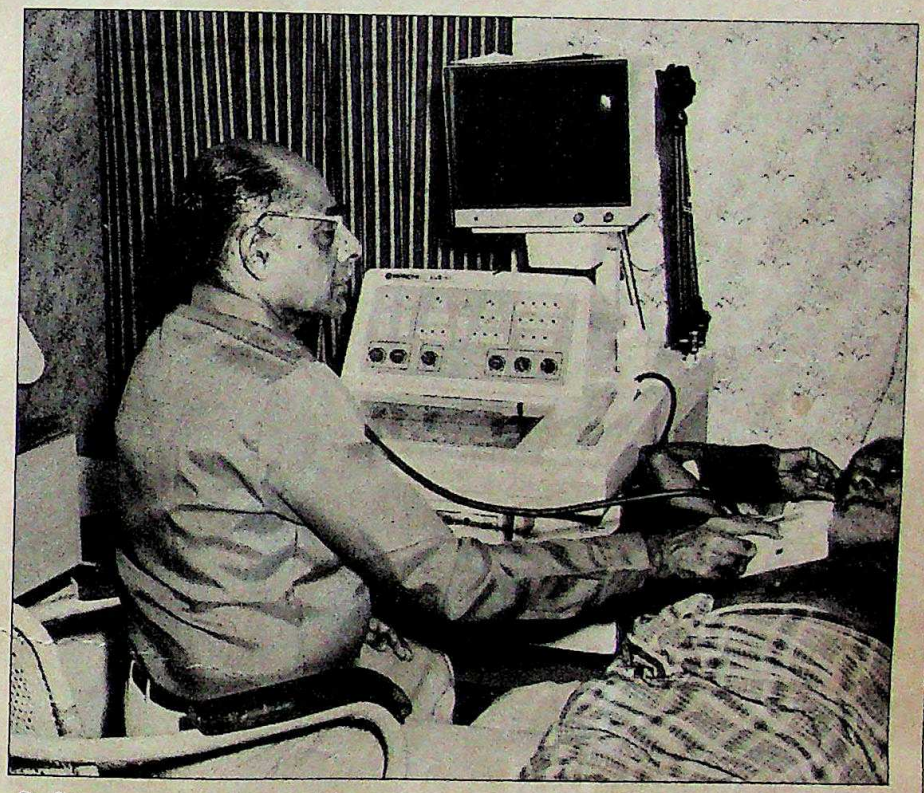

निजी अस्पताल: आधुनिक यंत्रों पर जोर

आर्थिक और सांख्यिकीय ब्यूरो ने 1986 में एक सर्वेक्षण किया था. इसके अनुसार, "केरल में 1953 सरकारी अस्पतालों के 38,133 बिस्तरों के मुकाबले निजी क्षेत्र में 3585 अस्पताल हैं, जिनमें 50,766 बिस्तर हैं. राज्य के लगभग 70 फीसदी अस्पताल निजी क्षेत्र में हैं.

राज्य में निजी अस्पतालों की बाढ़ के साथ-साथ उच्च तकनीकी उपकरणों की मांग भी तेजी से बढ़ी है. निजी क्षेत्र के सभी अस्पताल चाहे दूरदराज के गांवों में हों या बड़े शहरों में, स्वयं को परिष्कृत चिकित्सकीय उपकरणों से लैस करने में जुटे हैं. उदाहरण के लिए त्रिवेंद्रम का 50 बिस्तरों वाला नया श्री उतरादम तिरुमल अस्पताल राज्य के उन दो अस्पतालों में एक है, जहां आधुनिकतम उपकरणों से लैस कैथराइजेशन प्रयोगशाला है. कैथराइजेशन विधि से यह परखा जाता है कि किस मरीज की ओपन हार्ट सर्जरी करनी जरूरी है. इस अस्पताल को चलाने वाले डॉ. भारत चंद्रन का कहना है कि "अपोलो अस्पताल में कोरोनरी बायपास सर्जरी की फीस 40,000 रुपए है जबकि हम पूर्व परीक्षण सहित इस ऑपरेशन के लिए कुल मिलाकर 25,000 रुपए ही लेते हैं." यहां औसतन 20 कोरोनरी बायपास ऑपरेशन प्रतिमाह कराने की योजना है.

उच्च तकनीकी चिकित्सा सुविधाओं की मांग गांवों में भी बढ़ती जा रही है. कांगाडा गांव के अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. सैमुअल जोसफ बताते हैं कि "गांव के लोग भी अब उच्चस्तरीय तकनीकी परीक्षणों की मांग करने लगे हैं. इलाज ठीक हो तो वे जितना पैसा लगे, देने को तैयार रहते हैं." पतनामातिट्टा जिले के सिर्फ 15,000 की आबादी वाले कोडनचेरी गांव में ही इस समय आधा दर्जन विशिष्ट अस्पताल हैं. 1980 में इस जिले में केवल 89 निजी अस्पताल हुआ करते थे. अब यह

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

संख्या 231 तक पहुंच गई है.

आज हालत यह है कि इस राज्य में सरकारी अस्पतालों के 45,000 डॉक्टरों के मुकाबले निजी अस्पतालों में 6,345 डॉक्टर काम कर रहे हैं. अधिकांश निजी अस्पताल अपने कनिष्ठ डॉक्टरों को 6,000 रुपए प्रतिमाह वेतन के अलावा मकान भी मुहैया कराते हैं. बड़े अस्पताल का कोई विशेषज्ञ डॉक्टर 25,000 रुपए प्रतिमाह तक कमा सकता है. एक युवा डॉक्टर ने बताया कि मरीजों को कैट स्कैनिंग के लिए एक खास अस्पताल में भेजने पर उसे उस अस्पताल से प्रति मरीज 250 रुपए कमीशन मिल जाता है. इसके अलावा कई बड़े अस्पताल हरेक बायपास सर्जरी तथा गुर्दा प्रत्यारोपण से मिलने वाली फीस का दस प्रतिशत डॉक्टरों को भी देते हैं. इस व्यवस्था से न केवल गला-काट प्रतियोगिता पनपी है बल्कि कुछ डॉक्टर तो मरीज को महंगे-से-महंगे इलाज के लिए भी बाध्य करने लगे हैं.

लेकिन बाकी डॉक्टर, जिनमें कोचीन के 15 वर्ष पुराने मेडिकल ट्रस्ट हॉस्पिटल के कर्ताधर्ता पी.ए. वर्गीज भी सम्मिलित हैं, इस आरोप को सही नहीं मानते. उनका कहना है चूंकि अधिकांश मलयाली शिक्षित हैं इसलिए उन्हें कोई आसानी से उल्लू नहीं बना सकता. वर्गीज कहते हैं, "मेरे कुछ मरीज तो अपने साथ अपनी बीमारी से संबंधित साहित्य भी साथ लाते हैं. इलाज के उच्च तकनीकी विवरण से वे भलीभांति परिचित होते हैं. वे ही हमें व्यापारी बनने को मजबूर करते हैं. यदि परिष्कृत उपकरणों से उनकी जांच न करें तो वे दूसरे अस्पतालों में चले जाएंगे." हालत यह है कि इलाज में कोई गड़बड़ी होने पर डॉक्टर को जिम्मेदार तक ठहराया जाने लगा है. यही वजह है कि कई डॉक्टरों ने व्यावसायिक चूक से मुक्ति पाने के लिए बीमा भी करवा लिया है.

क्या इन सबका यह अर्थ लगाया जाए कि मलयाली अपनी शिक्षा और बुद्धिमत्ता के बावजूद निजी अस्पतालों के हाथों लुटे जा रहे हैं. कोचीन में सिटी अस्पताल चलाने वाले डॉ. टी.एम. पाल इसे नहीं मानते बल्कि उनका कहना है कि निजी अस्पताल सार्वजनिक महत्व का काम कर रहे हैं. राज्य की सुस्त तथा भ्रष्ट जनस्वास्थ्य सेवा के कारण ही निजी अस्पताल तेजी से पनप रहे हैं. डॉ. पाल कैफियत देते हैं कि "एक ऑटोरिक्शा चालक भी जानता है कि सरकारी अस्पताल में डॉक्टर तथा नर्स को रिश्वत दिए बिना उसका विधिवत इलाज नहीं हो पाएगा. वह हमारे पास आता है क्योंकि बेहतर तीमारदारी और आधुनिकतम चिकित्सा के बदले में उसे एक ही बिल चुकाना पड़ता है." डॉ. पाल के कथन की पुष्टि इसी बात से हो जाती है कि "एक भी सरकारी अस्पताल में कैट स्कैनर की सुविधा नहीं है जबकि निजी क्षेत्र में कम-से-कम पांच कैट स्कैनर हैं."

कुमार स्टूडियो

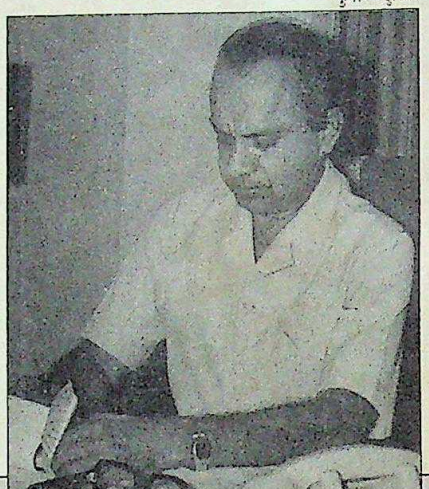

"कुछ मरीज डॉक्टरों को व्यापारी बनने पर मजबूर करते हैं. आधुनिक यंत्रों से उनकी जांच न हो तो दूसरे अस्पताल में जाने को तैयार रहते हैं"

पी.ए. वर्गीज
मेडिकल ट्रस्ट हॉस्पिटल, कोचीन

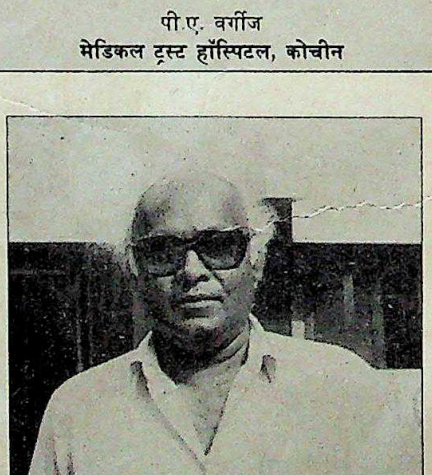

"एक ऑटोरिक्शा चालक भी जानता है कि सरकारी अस्पताल में डॉक्टर और नर्स को रिश्वत दिए बिना इलाज नहीं होता. तभी वह हमारे पास आता है"

टी.एम. पॉल
सिटी हॉस्पिटल, कोचीन

लेकिन कुछ निजी अस्पताल गड़बड़झाले से परे नहीं लगते. अस्पताल खोलने के लिए कोई अनिवार्य कानूनी इजाजत तो लेनी नहीं पड़ती इसलिए जहां-तहां निजी अस्पताल खुल रहे हैं. दुकानों और महलों तक में अस्पताल देखे जा सकते हैं. इस धंधे का अब इतना व्यवसायीकरण हो गया है कि निजी अस्पताल अपनी प्रतियोगी संस्थाओं से विशेषज्ञ डॉक्टरों को अधिक वेतन का लालच देकर बुलाते रहते हैं. जब भी कोई डॉक्टर अथवा अस्पताल कोई नया उपकरण खरीदता है तो उसे तुरंत ही अखबारों में विज्ञापित किया जाता है.

इसके बावजूद बैंक तथा केरल वित्त निगम जैसी वित्तीय संस्थाएं भी निजी अस्पतालों को 15 प्रतिशत की दर से 60 लाख रुपए तक का कर्ज मुहैया करा देती हैं. पिछले साल केरल वित्त निगम ने पांच निजी अस्पतालों को वित्तीय सहायता दी थी और अब उम्मीद है कि छह और ऐसे ही प्रस्तावों को भी जल्द ही हरी झंडी दिखा दी जाएगी.

निजी अस्पतालों की बढ़ती तादाद से सबसे अधिक नुकसान सरकारी अस्पतालों का हुआ है. वेतन के आकर्षण से डॉक्टर, नर्स तथा टेक्नीशियन सरकारी संस्थाओं को छोड़कर निजी अस्पतालों की ओर खिंचे जा रहे हैं. यह भी गौरतलब है कि इतनी अक्षमताओं और अव्यवस्थाओं के बावजूद केरल की जन स्वास्थ्य सेवा देश की बेहतरीन स्वास्थ्य सेवा है. राज्य सरकार अब निजी अस्पतालों के इस फलते-फूलते धंधे पर अंकुश लगाने की योजना बना रही है. मार्क्सवादी सरकार के पहले बजट में निजी अस्पतालों पर प्रति बिस्तर एक हजार रुपए टैक्स लगाने का प्रावधान था.

विश्व में कहीं बीमारी पर टैक्स नहीं है. निजी अस्पतालों ने इस फैसले को अदालत में चुनौती देना तय किया है. [illegible] स्वास्थ्यमंत्री षणमुखदास [illegible] अस्पतालों पर वैधानिक अंकुश लगाने को कटिबद्ध हैं. जब तक लोग निजी अस्पतालों को मोटी रकम देते रहेंगे, यहां काम करने के लिए डॉक्टर मौजूद रहेंगे, तब तक सरकार उनकी बढ़त रोक नहीं पाएगी.

—श्रीधर [illegible]

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

महर्षि महेश योगी

अधर में पड़ा अध्यात्म

आयकर छापों और सरकारी नोटिसों से गुरु परेशान

महर्षि महेश योगी के अनुयायियों ने अपने गुरु की पिछले साल की घोषणा के अनुसार 12 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय शांति वर्ष मनाया. मगर यह पूरा साल जेट युग के इस योगी के लिए और चाहे कैसा भी रहा हो पर शांतिपूर्ण नहीं रहा. विभिन्न समस्याओं के चलते दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा 'थीम पार्क' बनाने की महत्वाकांक्षी योजना शुरू नहीं हो सकी.

साल के अंत में दिल्ली और उसके आसपास तथा योगी के पैतृक शहर जबलपुर में उनके संस्थानों पर आयकर विभाग ने कई छापे मारे. बताया जाता है कि 50 लाख से ज्यादा की नकदी, जेवर, शेयर व एफडीआर जब्त किए गए. सिर्फ विदेशी मुद्रा ही करीब दो लाख रुपए की थी. जब्त दस्तावेजों से यह भी संकेत मिलता है कि निवेश करोड़ों में है और योगी के रिश्तेदारों व अनुयायियो के ट्रस्टों द्वारा दिखाया गया खर्च वास्तव में कहीं खर्च किया ही नहीं गया.

आयुर्वेद को बढ़ावा देने की आश्रम की कोशिशें तब विवाद में फंस गईं जब 21 जून को गैस की तकलीफ के बाद एक 14 वर्षीय छात्र लव कुमार चौबे की मृत्यु हो गई. उसका इलाज आयुर्वेदिक डॉक्टरों ने किया था. इससे पहले दिल्ली के करीब महर्षिनगर के स्कूल में संस्कृत और वैदिक अनुष्ठान के शिक्षकों ने एक यूनियन गठित कर ली और बेहतर वेतन व कामकाज की सुविधाओं की मांग की. अखबारों ने भी सख्ती बरती और वे आश्रम के छात्रों व अध्यापकों की दुर्दशा पर विस्तार और तल्खी से लिखते रहे. तीन महीने तक स्कूल बंद रहा. इसके 2000 छात्रों को उनके घर अथवा ऋषिकेश वाले आश्रम भेज दिया गया. कुछ समय के लिए खुद योगी भी आश्रम के अपने कुटीर से नई दिल्ली की पॉश कालोनी गोल्फ लिंक्स स्थित महिला ध्यान पीठ में चले गए.

चार्ट: बी.के. शर्मा

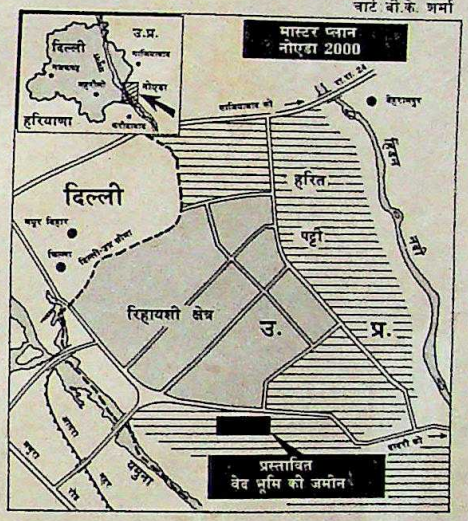

प्रशांत पंजियार

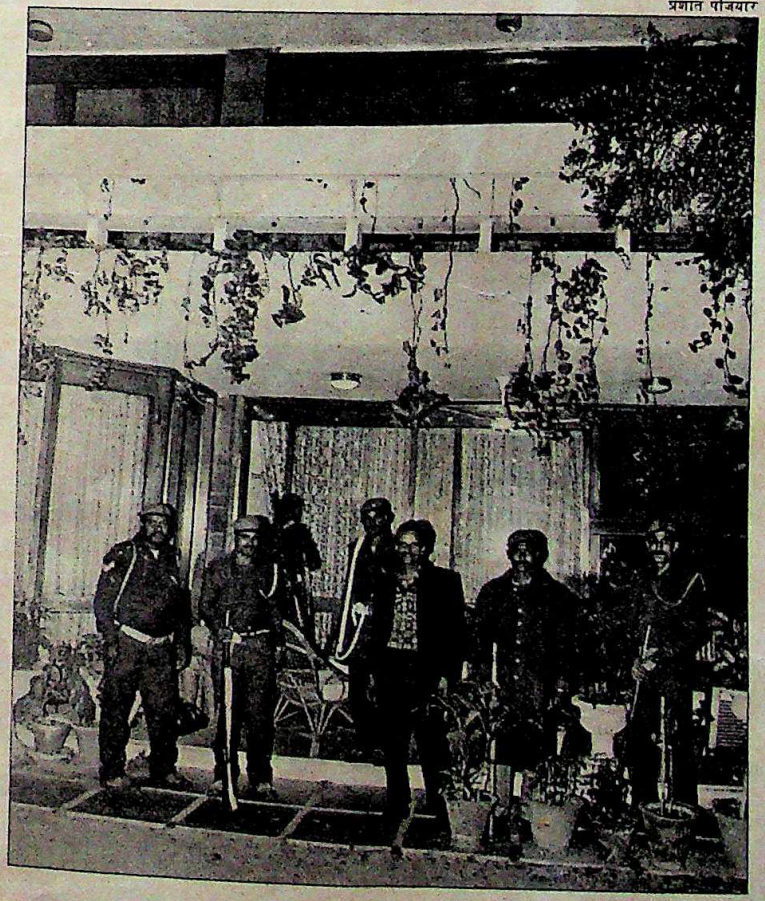

दिल्ली में महेश योगी के घर छापा

आश्रम के लिए शायद सबसे बड़ा सिरदर्द तो वह जमीन ही है जिस पर आश्रम बना है. आश्रम उस हरित पट्टी के बीच पड़ता है जो नोएडा के चारों ओर बनानी तय की गई थी. विभिन्न ट्रस्टों और योगी के अनुयायियों ने पिछले दशक के अंतिम वर्षों में यमुना-हिंडन संगम के करीब इस उर्वर हरित पट्टी में जमीन लेना शुरू किया. उन्होंने सैकड़ों एकड़ जमीन जुटा ली. 1983 में सरकारी अधिकारियों की नींद खुली और उन्होंने आश्रम का निर्माण रोकने के आदेश दिए.

स्थानीय सरकारी नोटिसों पर बार-बार आश्वासन दिया गया कि निर्माण रोक दिया जाएगा. कई नोटिसों, आश्वासनों के बाद सरकार ने भूमि अधिग्रहण की कोशिश की. आश्रम अधिकारियों ने भूमि में छूट देने की गुजारिश की और हाईकोर्ट की इलाहाबाद व लखनऊ खंडपीठों में छूट की मांग करते हुए याचिकाएं भी दाखिल कर दीं. इस तरह सरकारी आदेशों पर रोक लग गई.

इस जमीन पर लगे प्रश्नचिन्ह के कारण आश्रम की 'वेदभूमि' परियोजना पर ब्रेक लग गए. वेदभूमि में आध्यात्मिक जागरण, ज्ञान और मनोरंजन तीनों के समावेश की योजना है. कनाडियन जादूगर डगलस हेनिंग (देखें बाक्स), जो इस मायाजाल के निर्माण के लिए यहां आए हुए हैं, इस परियोजना को लेकर आशान्वित हैं. सरकारी एजेंसियों की बाबत वे कहते हैं, "वे सभी इसे लेकर बेहद उत्साहित हैं. हमें मंजूरी मिलने की पूरी उम्मीद है." आश्रम के दूसरे अधिकारी कहते हैं कि 220 करोड़ की इस परियोजना को वे जरूर पूरा करेंगे.

आखिरकार इस सबका मकसद पर्यटन से है. प्रवेश टिकट पांच रुपए की होगी और उन्हें उम्मीद है कि रोजाना 7000 से 15,000 के बीच दर्शक आएंगे. विदेशी लोग, 'जो पैसे की चिंता नहीं करते,' उम्मीद है कि पार्क के विभिन्न आकर्षणों पर प्रति व्यक्ति 250 रुपए खर्च करेंगे. 200 एकड़ के पार्क

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

में चारों ओर हिंदू प्रतीकों के भौंचक कर देने वाले नमूने फैले होंगे. इस पार्क में प्रवेश ही 'कैलाश पर्वत' से होगा, जिसके बाद दर्शक माणिक व पन्नों जड़ी गुफाओं से गुजरेंगे. एक महत्वपूर्ण चीज नारायण मंडप होगा. पर्वत के ऊपर जाते हुए दर्शकों को इस ध्यान की सातों अवस्थाओं के दर्शन होंगे. "फिर आपकी नाव पर्वत से नीचे इंद्रधनुष, ओस और प्रकाश में उतरेगी," हेनिंग कहते हैं, "यह धरती पर स्वर्ग का प्रतीक होगा, क्योंकि महर्षि के अनुसार आध्यात्मिक जागरण मिलने के बाद आप धरती पर आते हैं."

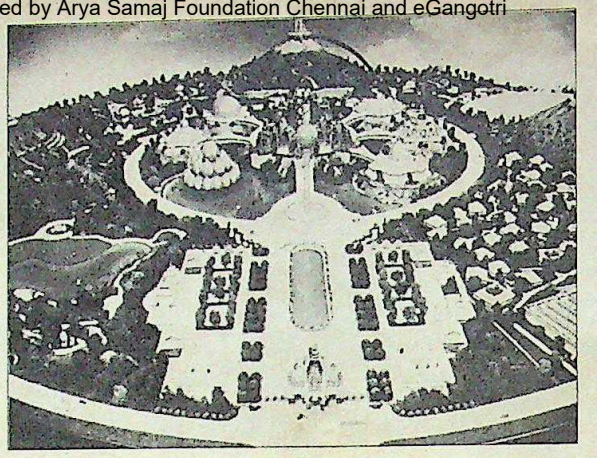

वेदभूमि का मॉडल

वास्तव में यह पूरा तामझाम आध्यात्मिक जागरण के लिए ही है. हेनिंग के शब्दों में, "महर्षि हमें बताते हैं कि ध्यान की ये अवस्थाएं कैसी हैं और हम उच्च टेक्नालाजी की मदद से वैसा ही माहौल पैदा कर देते हैं." मसलन, उनके मुताबिक, ईश्वरीय ध्यान कक्ष में दर्शक का स्नायु तंत्र इतना परिष्कृत हो जाएगा कि उसे दिव्य अनुभूतियां होंगी और वह देवताओं व ईश्वर को देख सकेगा. हेनिंग के मुताबिक, "हम ऐसा करने जा रहे हैं कि इंद्र और दूसरे देवता नीचे आकर आपको स्पर्श करेंगे."

यह सब बनाने के लिए, "हमारे पास दुनिया का एक बेहतरीन कंप्यूटोग्राफिक्स स्टुडियो होगा," हेनिंग कहते हैं, "हमारे पास करोड़ों के कंप्यूटोग्राफिक्स के प्रोग्राम होंगे जिनसे कंप्यूटर त्रि-आयामी आकृतियां पैदा कर सकता है जो सजीव दिखती हैं."

आश्रम अधिकारियों ने छापों से पहले स्वीकार किया था कि इस सबके लिए पैसा कोई समस्या नहीं है." छापे और दूसरी समस्याओं के लिए आश्रम के लोग जिम्मेदार हैं या स्थानीय सरकारी एजेंसियां, यह एक बड़ा सवाल है. —डेविड देवदास

डगलस हेनिंग

तकनीकी जादू

डगलस जेम्स हेनिंग ने 1961 में 14 वर्ष की उम्र में जादूगर के रूप में अपना जीवन शुरू किया था. तब से अमेरिकियों को चमत्कृत करने, ब्रुक शील्ड्स और बिल कोस्बी जैसे हॉलीवुड के सितारों के साथ काम करने और पॉप संगीत के सबसे बड़े सितारे माइकल जैक्सन को भी अपने जादू से 'वश' में कर चुकने के बाद समूचा अमेरिका उन्हें 'आधुनिक युग का सबसे बड़ा जादूगर' मानने लगा था.

पर प्रति हफ्ते एक लाख डॉलर तक की कमाई-धमाई छोड़कर आजकल वे अपनी पत्नी डेब्बी के साथ महेश योगी के दिल्ली के बाहर नोएडा में महर्षिनगर आश्रम में जमे हुए हैं. वे 1975 से ही उनके संपर्क में हैं और उनसे भावातीत ध्यान के जरिये सिद्धि प्राप्त करने का 'असली जादू' सीख रहे हैं. अब यह दंपती अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल 'वेदभूमि' बनाने में कर रहा है. दुनिया का यह सबसे बड़ा पार्क बनाने में डगलस और डेब्बी मनोरंजन की उच्च तकनीक इस्तेमाल करेंगे इसमें कंप्यूटर, तीन आयामी फिल्मों और दूसरी तकनीकों का भी उपयोग होगा. और इसके जरिये महर्षि के वैदिक ज्ञान को लोगों तक पहुंचाया जाएगा.

अनुभवों और वाहवाहियों ने 40 वर्षीय हेनिंग का दिमाग खराब नहीं किया है. उनके चेहरे पर बालसुलभ कोमलता दिखती है और 'वेदभूमि' की बात करते हुए वे उत्साह से भरे होते हैं. डेब्बी और

प्रशांत पत्रियार

हेनिंग दंपती: भारतीयता की छाप

वे खुद देसी रेशम की पोशाक पहनते हैं और भारतीय अतिथि सत्कार का गुण भी उन्होंने आत्मसात कर लिया है. 38 वर्षीया डेब्बी, जो 18 वर्ष की युवती लगती हैं, किसी औसत भारतीय पत्नी की तरह अपने पति को चाय पिलाती हैं, उनकी चीजें ला देती हैं और आश्रम का कोई बड़ा-बुजुर्ग आ जाए तो उसके लिए अपनी सीट खाली कर देती हैं.

कनाडा के एक छोटे कस्बे विनीपेग से अपना जीवन शुरू करने वाले डगलस ने हालांकि मेडिकल पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी पर तब तक उन्होंने मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को ठीक से जान जरूर लिया था. उनका मानना है कि वे नए दौर के जादूगर हैं, ऊंची टोपी या लंबे कोट वाले जादूगरों की परंपरा, जादू-टोने के माहौल के साथ ही शोर-शराबे वाली जादूगरी उन्होंने कब की पीछे छोड़ दी है. उनके कई खेल काफी प्रचलित भी हैं. जैसे लड़की को हवा में उठा देना, उसे आरे से काटकर जोड़ना, बक्से से हाथी गायब कर देना और एक हाथ में रखे बटन को जादू से दूसरे में पहुंचा देना. महान जादूगर हुडनी की तरह वे भी बक्से में बंद करके पानी में डाल दिए जाने के तुरंत बाद बाहर निकल आते हैं. डगलस कई बार तो पानी के अंदर शार्क मछली में बदल जाने का खेल भी दिखाते हैं.

इन सबमें कोई रहस्य नहीं है. यह पेशेवर कुशलता का कमाल है. यह सब कैसे होता है, यह वे नहीं बताएंगे पर उनका मानना है कि यह किसी अलौकिक शक्ति का खेल नहीं है. वे कहते हैं, "जादूगर का काम कुतूहल जगा देने भर है. और कुतूहल का भाव जब तक रहेगा, हमारा जीवन अधिक सुखमय होता रहेगा." —डेविड देवदास

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj F

खूबसूरती तो बस एक पहलू है स्पारटेक फ़्लोर्स का.

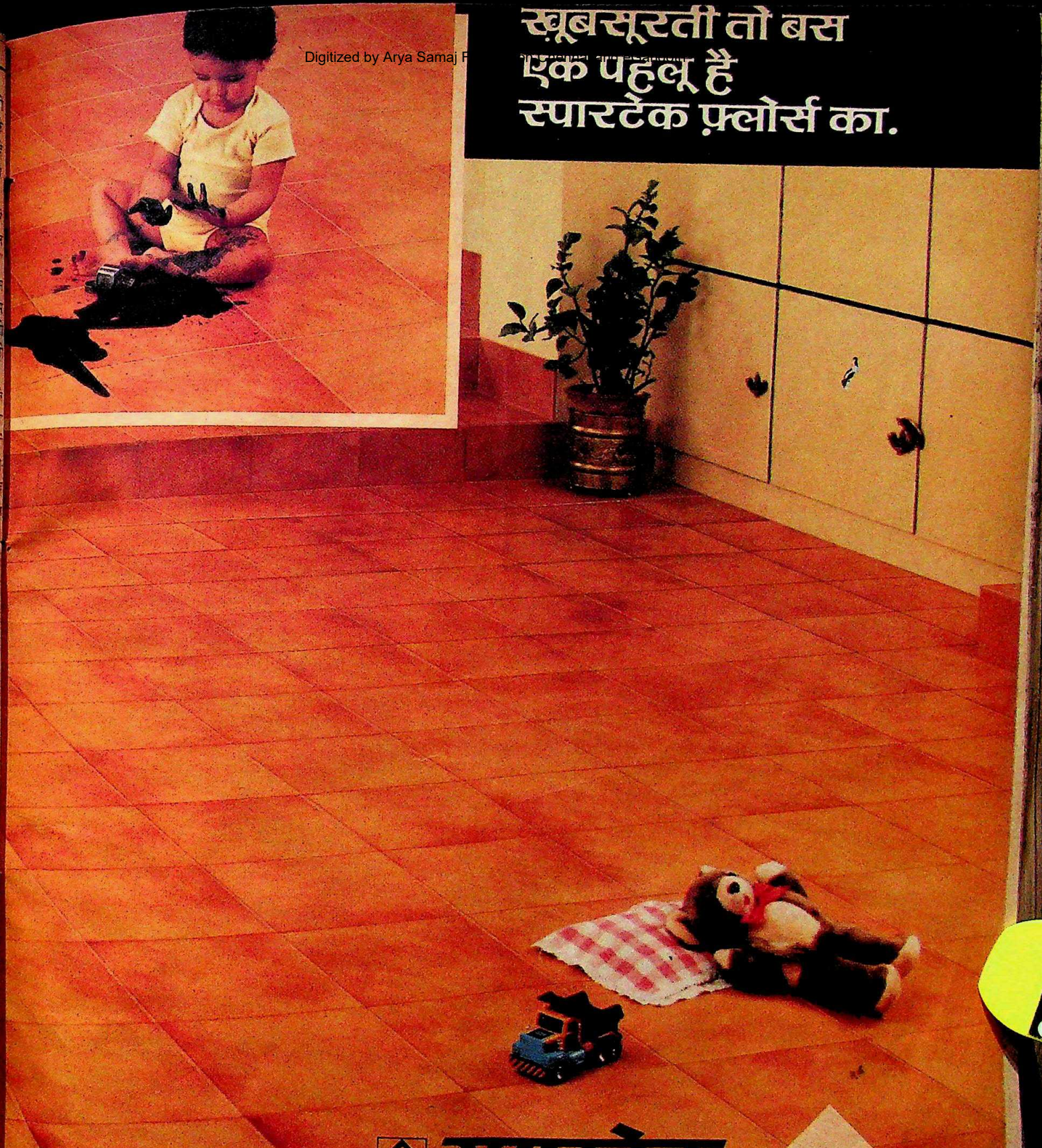

स्पारटेक

५२, चेमियर्स रोड, मद्रास-६०० ०२८

भारत में सबसे ज़्यादा बिकनेवाले सिरामिक फ़्लोर टाइल्स

दाग-धब्बों से बेअसर भी हैं.

ग़ौर से देखिए और जानिए स्पारटेक फ़्लोर्स के गुण...
खरोंच से पूर्ण तरह बेअसर ● दाग-धब्बों से बेअसर
पानी और आंच से बेअसर ● देखरेख और सफ़ाई आसान
सूना फ़र्श पर भी आसानी से लगाये – बिठाये जा सकते
४८ घंटों में ही फ़र्श इस्तेमाल कर सकते हैं ● अनेकों

साइज़ों में उपलब्ध – 305 x 305 mm, 305 x 203 mm, 203 x 203 mm, 203 x 101.5 mm – एक से बढ़कर एक मनभावन रंगों में.

ये सारी खूबियां और खूबसूरती ऐसी कि आप देखते रह जाएं.

स्पारटेक फ़्लोर्स – दिखने में खूब, इस्तेमाल में खूब, हर पहलू से खूब.

INTAS M SGL P 12 2720 HI

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारत के सबसे बड़े, आधुनिकतम कलर पिक्चर ट्यूब उद्यम – अपट्रॉन सीपीटी – के साझीदार हैं – विश्व अग्रणी तोशीबा तथा मित्सूबिशी

निर्गम प्रारंभ
प्रवासी भारतीयों के लिए 26 जनवरी 1988
भारतीय जनता के लिए 1 फरवरी 1988

निर्गम के प्रबंधक

एस बी आई कैपिटल मार्केट्स लि

इंडस्ट्रीयल क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन आफ इण्डिया लि. मर्चेंट बैंकिंग डिविजन

निर्गम के सह प्रबंधक

बैंक आफ इण्डिया

यूनियन बैंक आफ इण्डिया मर्चेंट बैंकिंग डिविजन

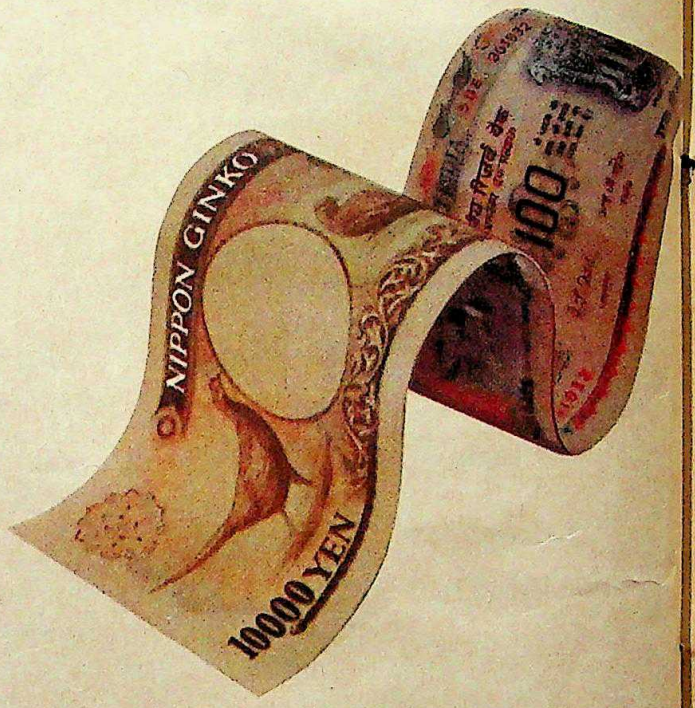

अब, अपट्रॉन सीपीटी, आपका भी ए
साझीदार के रूप में सहर्ष स्वागत क

एक आयात विकल्प योजना

UPTRON®
COLOUR PICTURE TUBES

अपट्रॉन कलर पिक्चर ट्यूब्स लि. ● पंजीकृत कार्यालय: 10, अशोक मार्ग लखनऊ-226001 ● मुख्य कार्यालय : एम/41-42, मेन मार्ग

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

UPTRON

एक शानदार निवेश अवसर – अपट्रॉन कलर पिक्चर ट्यूब्स, निश्चित सफलता के तत्वों का मेल।

विशिष्ट प्रवर्तक

अपट्रॉन, तोशीबा एवं मित्सुबिशी – शानदार उपलब्धियों वाले अग्रणी।

अपट्रॉन, भारत के प्रतियोगी इलेक्ट्रानिक्स उद्योग में सर्वाधिक उन्नति दर वाला एक उद्यम। 1979-80 में कारोबार रु. 3 करोड़, 1986-87 में बढ़कर रु. 97 करोड़ तथा 1987-88 में और भी बढ़कर रु. 160 करोड़... तथा 1989-90 में सम्भावित रु. 300 करोड़ (अपट्रॉन सीपीटी को छोड़कर)।

तोशीबा एक अन्तर्राष्ट्रीय विख्यात विशाल औद्योगिक समूह, विश्व में रंगीन पिक्चर ट्यूबुस (सीपीटीज) के सब से बड़े निर्माता। विश्व भर में 1 करोड़ 50 लाख सीपीटीज का उत्पादन तथा विश्वभर में 20% से अधिक सप्लाई। तोशीबा का सम्पूर्ण कारोबार लगभग रु. 30,000 करोड़।

मित्सुबिशी जापान का सबसे बड़ा औद्योगिक समूह – एक बहु-उद्देशीय, बहु-उत्पाद, बहु-पक्षीय ग्रुप जिसके विशाल व्यापार एवं वैज्ञानिक हित हैं।

भारत का सबसे बड़ा सीपीटी प्रॉजेक्ट

रु 117 करोड़ की लागत तथा 7,50,000 रंगीन पिक्चर ट्यूब्स क्षमता के साथ अपट्रॉन सीपीटी, भारत का सबसे बड़ा सीपीटी प्रॉजेक्ट तथा साथ ही भारत का सबसे बड़ा आधुनिकतम इलैक्ट्रानिक उपकरण उद्यम भी है।

विश्व की सर्वोत्तम टैक्नॉलेजी

तोशीबा की ओर से – जो सीपीटी क्षेत्र में प्रवर्तक तथा अद्वितीय अग्रणी है। तोशीबा के अनूठे नवीन उत्पादनों में शामिल है – प्रथम मिनी नैक ट्यूब, प्रथम ब्लैक स्ट्राईप परत वाला स्क्रीन, प्रथम पूर्ण चपटी चौकोर (एफ एस) ट्यूब, लेसर टैक्नालोजी के प्रयोग द्वारा क्रियाशील प्रथम इलेक्ट्रॉन गन। सभी टीवी को बेहतर कार्यशीलता एवं टीकाउपन को विश्वसनीय बनाने के लिए।

तोशीबा की अद्वितीय तकनीक एवं जानकारी, जिसकी अमरीका, पूर्व जर्मनी, चैकोस्लोवाकिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान एवं चीन समेत विश्व के आधुनिकतम इलैक्ट्रानिक्स मार्केट में भी बड़ी मांग है, अब पहली बार भारत में भी उपलब्ध, जिस से अपट्रॉन सीपीटी को भारतीय मार्केट में अद्वितीय प्रभुता प्रदान होगी।

आधुनिकतम प्लान्ट, क्रान्तिकारी उत्पादन

नवीनतम, स्वचालित, आधुनिकतम प्लांट – जिस प्रकार के प्लांट तोशीबा ने वैस्टिंग हाऊस अमरीका तथा अन्य को सप्लाई किए हैं, भारत में पहली बार क्रान्तिकारी मिनी-नैक, चपटी चौकोर एवं ब्लैक मैट्रिक्स ट्यूब्स के निर्माण के लिए।

तेज़ी से विकासशील मार्केट

भारत में रंगीन टेलीविज़न सैटों की मांग 1983 में 50,000 से बढ़कर आज 9,00,000 हो गई है – तथा 1990 तक बढ़कर यह 20,00,000 सैट होने की आशा। इस प्रकार अपट्रॉन सीपीटी के पास उसके पूरे वार्षिक उत्पादन के लिये तैयार मार्केट उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त कंपनी के पास अपट्रॉन इन्डिया लिमिटेड के लिये काफी मात्रा में सीपीटी सप्लाई करने की निश्चित मार्केट भी होगी।

आयात विकल्प

अब तक सीपीटी आयात किए जाते रहे हैं। इस कारण अपट्रॉन सीपीटी, 100% आयात विकल्प प्रांजेक्ट, की बिक्री सम्भावनाएं और भी सुनिश्चित हैं।

उत्पादन पहले ही आरंभ

उत्पादन आरंभ हो चुका है तथा लगभग 10 करोड़ का बिक्री भी हो चुकी है। पूर्ण क्षमता पर कार्यशील होने पर प्रोजेक्ट का कारोबार रु. 180 करोड़ वार्षिक से अधिक होगा।

आदर्श स्थल

साहिबाबाद–दिल्ली (कनॉट प्लेस) से केवल 22 कि.मी. दूर – सीपीटी मार्केट का केन्द्र, जहां भारत में उत्पादित 35% से अधिक रंगीन टीवी सेट निर्मित किये जाते है।

निवेशक लाभ

80 सी सी, 80 एल, 80 एम तथा संपत्ति कर लाभ, भुनाना आसान – अहमदाबाद, बैंगलोर, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, कानपुर एवं मद्रास स्टांक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध।

विश्वसनीय आय सम्भावनाएं

जी हां, अपट्रॉन सीपीटी की आय सम्भावनाएं विश्वनीय है। आइए, हमारे प्रतिष्ठित उद्यम में साझीदार बनिए।

एक उच्च प्रगतिशील इलैक्ट्रॉनिक्स शेयर

रु. 10/- प्रति के 1,92,90,000 इक्विटी शेयरों का सममूल्य पर सार्वजनिक निर्गम

Sobhagya/321/87/H

TOSHIBA – Mitsubishi Corporation

-110 048

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शबनम के साथ शिखा (बाएं)

◆ विमल फैब्रिक्स और हीरो साइकिलों के विज्ञापनों में झलकने वाली 20 वर्षीय मॉडल **शिखा स्वरूप** ने अबकी बार तो कमाल ही कर दिया. 5 फीट 10 इंच ऊंची, छरहरे बदन की यह लड़की 'ईव्ज वीकली' और जे.के. हेलन कर्टिस द्वारा आयोजित सौंदर्य स्पर्धा में 'मिस इंडिया 1988' का खिताब झटक ले गई. दूसरे नंबर पर रहीं बंबई की 18 साला फैशन डिजाइनर **शबनम पटेल.** पर दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ रही शिखा के लिए इस ने एक समस्या भी खड़ी कर दी है कि "परीक्षा दूं या सौंदर्य के बूते मिलने वाले काम करूं," पर इसके साथ ही वह जोड़ती है, "मेरी राशि तुला है इसलिए संतुलन कायम करने की कोशिश करूंगी."

◆ क्या फिल्मी पुनर्मिलन है! पिछले दशक में प्रणयसूत्र में बंधे **डिंपल कपाड़िया** और **राजेश खन्ना** चार साल जुदा रहने के बाद 'जय शिवशंकर' फिल्म में फिर एक साथ होंगे. राजेश, सरकार विरोधी एक अखबार के संपादक की भूमिका निभा रहे हैं और उनके 'सपनों की रानी' जिला कलेक्टर है. 'पेशागत समझौते' की कोशिशें डिंपल की ओर से ही शुरू हुई. डिंपल कहती हैं, "मुझे पता चला वे फिल्म बना रहे हैं तो मैंने उनसे इसमें भूमिका मांगी और वे तुरंत राजी हो गए." और जब सचमुच शूटिंग शुरू हुई तो परदे की सफल नायिका को पसीने छूटने लगे, "सीधे उनकी आंखों में झांकने के लिए मुझे पूरा साहस जुटाना पड़ा." पर दूसरी ओर राजेश का कहना था, "आखिर मैं अभी भी उसका खाविंद हूं."

डिंपल और राजेश: पुनर्मिलन

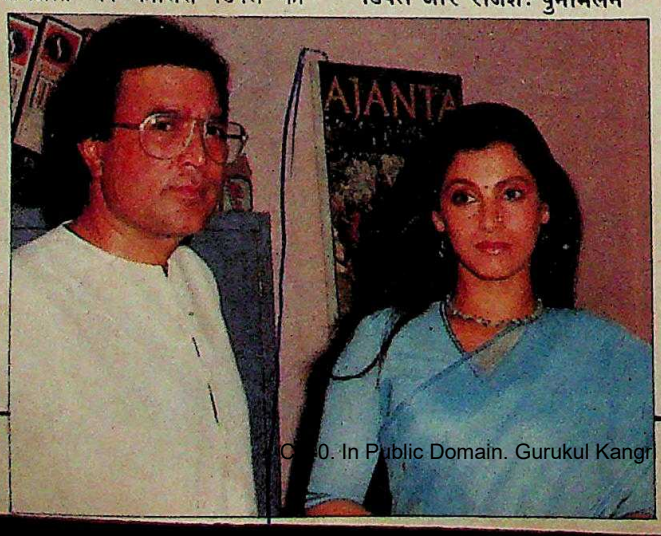

गौतम और जैल सिंह: आत्मकथा

◆ इस बार **ज्ञानी जी** जानी-पहचानी भूमिका में हैं. उनके जीवन पर एक डाक्यूमेंट्री फिल्म 'युग पुरुष' बन रही है. इसमें दिखाया जाएगा कि कैसे वे बढ़ई से आजादी के सिपाही, फिर नेता बने और आखिरकार देश के सर्वोच्च पद तक जा पहुंचे. फिल्म निर्माता पट-कथा लेखन, और आजादी से पहले के दिनों के उनके साथी 77 वर्षीय **मंगलानंद गौतम** बताते हैं, "मैं इसमें बुलंदियां छू लेने वाले एक साधारण व्यक्ति का चित्रण कर रहा हूं." और यह फिल्म भी पारिवारिक ढंग से बन रही है. गौतम के बेटे **अजीत** इसके निर्देशक हैं तो उनके पोते **अनिल** ज्ञानी जैल सिंह की जवानी का रोल कर रहे हैं. गौतम ने कहा, "लिंकन और लेनिन की तरह ज्ञानी जी ने भी बहुत मामूली स्तर से शुरुआत की थी. लोकतंत्र में यही तो सबसे अच्छी बात है."

◆ तेजी से चलना उनकी खासियत है और जब वे शतरंज के चौखानों पर तेजी से चलते हैं तो अच्छे-अच्छों की कयामत आ जाती है. 18 बरस के राष्ट्रीय शतरंज चैंपियन **विश्वनाथन आनंद** ऐसे ही खिलाड़ी हैं. भारत ही नहीं बल्कि एशिया में भी पहली बार विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन का खिताब जीतने का उनका करिश्मा लोगों की स्मृति में ताजा ही था कि आनंद ने पिछले महीने कोयंबतूर में एक और चमत्कार कर दिखाया. अब वे भारत के पहले और दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रैंडमास्टर हो गए हैं. आनंद कहते हैं, "निर्धारित समय से पहले ही यह खिताब जीतने

आनंद: प्रतिभाशाली

से मैं बहुत खुश हूं." 12वें बाजी उन्होंने हंगरी के पीटर लुकास के साथ ख़िताब जीता. आनंद ने सहजता से खेलता हूं." पर चालें एकदम सटीक रहती उन्हें मात देना सहज नहीं

मील के पत्थर

■ **निधन:** दुनिया में सबसे मूंछें रखने वाले राजस्थान वर्षीय **करणा भील** की हत्या गई. इस पूर्व डकैत ने 19 पहले एक कत्ल किया था, बदला उसकी गरदन काटकर

रघु राय

करणा: कत्ल

किया गया. किसी चक्र उसके गालों से चिपकी इंच लंबी मूछों को गिनीज जगह मिली हुई थी. जेल से के बाद वह भलेमानस जी रहा था. एक लोकवाद्य बजाने में महारत और कारण उसे काफी शोहरत पर सुधरे हुए इस अपराधी भी अपराध से ही हुआ.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digi... Arya Sar... ...gotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

REGISTRATION NO. R.N. 45823/86

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ज्यादा अमेरिका पैन एम से

ज्यादा शहर

पैन एम के विमानों से आप अमेरिका के न्यूयॉर्क, लॉस एंजिलिस, सैन फ्रांसिस्को, शिकागो, मियामी, डलास और वाशिंगटन डीसी सहित 30 शहरों तक पहुँच सकते हैं.

ज्यादा उड़ानें

दिल्ली और बंबई से पैन एम के 747 बोइंग विमानों में उड़ने का आनंद और हर विमान में तीन श्रेणियों में से किसी श्रेणी के चुनाव की सुविधा. और एक बार विमान में प्रवेश करते ही अपने घर जैसे माहौल का अनुभव क्योंकि आपकी सेवा के लिए मौजूद होते हैं भारतीय परिचारक और खासकर आपके लिए बनाए गए स्वादिष्ट भारतीय व्यंजन, और फिर विमान के अंदर घोषणाएं हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में.

ज्यादा सुविधाएं

पैन एम के वर्ल्डपोर्ट पर उतरते ही अमेरिका के दूसरे स्थानों के लिए संपर्क विमान सेवा तुरंत और आसानी से उपलब्ध. वर्ल्डपोर्ट न्यूयॉर्क के हवाई अड्डे पर एकमात्र टर्मिनल है जहां एक ही स्थान पर घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवा उपलब्ध है, यानी एक बार ही टिकट कटाने और प्रवेश की औपचारिकताओं से निबटने की सुविधा.

अतिरिक्त सुविधाएं

मिडटाउन मैनहटन और नेवार्क हवाई अड्डे के लिए पैन एम अपने फर्स्ट और क्लिपर® श्रेणी के यात्रियों को मुफ्त हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करता है. और स्वदेश लौटते हुए एक बार फिर वर्ल्डपोर्ट के हमारे नए टर्मिनल का विशिष्ट उपयोग करके आपको बहुत अच्छा लगेगा. वहां आपको किसी शानदार होटल की सुखदायी और व्यक्तिगत सेवा का सुख मिलेगा.

इसलिए अगर आप चाहते हैं कि अमेरिका आपकी अगली विमान यात्रा ज्यादा से ज्यादा आरामदेह हो तो पैन एम से आप इसकी आशा कर सकते हैं. सूचना और आरक्षण के लिए अपने एजेंट से संपर्क करें या पैन एम को फोन करें दिल्ली में 3325222, 3327804, तथा बंबई में 2029 2029048.

और भी अधिक की अपेक्षा पैन एम से

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

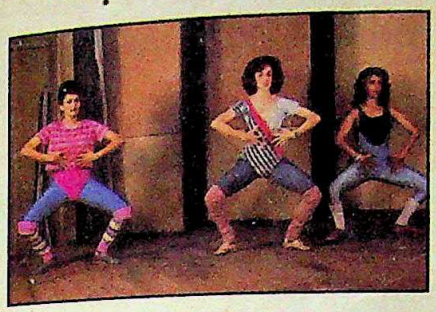

तंदुरुस्ती की बढ़ती तमन्ना

गरिष्ठ भोजन व मोटापे के गढ़ माने जाने वाले हिंदुस्तानी शहरों में इन दिनों 'हेल्थफूड्स', 'डाएट', 'जिम्नाजियम' और 'एक्सरसाइज़' जैसे शब्द फैशन बन गए हैं. चुस्त-दुरुस्त रहने के इच्छुक हर उम्र और आकार के लोग इन्हें आजमाने में लगे हैं. बदलते नजरिए पर नजर.

आवरण कथा 50

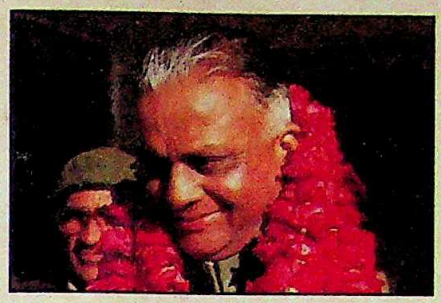

निकले बड़े बेआबरू होकर

राजस्थान के मुख्यमंत्री पद से हरिदेव जोशी को हटाया जाना दिल्ली दरबार द्वारा आयोजित सत्तापलट अभियान का ही परिणाम था. मजेदार बात यह रही कि शिवचरण माथुर को उनके स्थान पर ला बिठाने के फैसले को इंका विधायकों का समर्थन प्राप्त नहीं था.

खास रपट 42

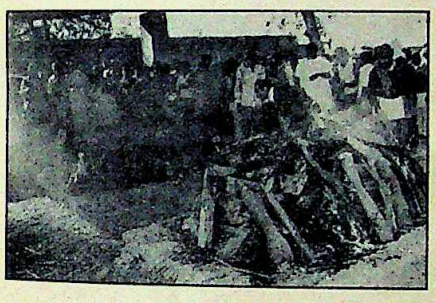

अंधियारा फिर घिर आया

पिछले महीने पंजाब में हत्याओं के नए दौर ने 1987 के अंत में हिंसा के घटते क्रम से बंधी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है. हत्याओं के इस नए दौर में जबकि आतंकवादी जहां जब चाहे अपने शिकारों को मार गिरा रहे हैं, वहां प्रशासन असहाय बना खड़ा है.

आजकल 18

सिंहासन के लिए संघर्ष

पिछले पखवाड़े मद्रास विधानसभा में मतदान के अहम सवाल के साथ ही जानकी और जयललिता के अन्ना द्रमुक गुटों की लड़ाई एक नाजुक दौर में प्रवेश कर गई. पेश है राज्य की राजनैतिक स्थिति का विश्लेषण और जानकी के साथ एक खास मुलाकात.

आजकल 22

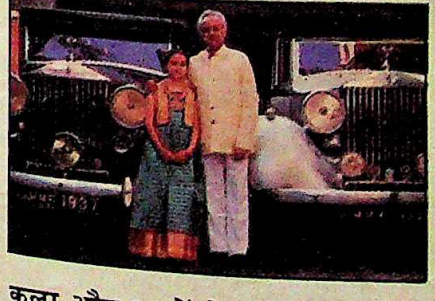

कला और कारों के शौकीन

भारत में उस शौकीन मिजाज के क्या कहने जिसे रॉल्स-रॉयस बटोरने का चस्का हो. कला-कृतियों और पुरानी कारों के रसिया प्राणलाल भोगीलाल का कार संग्रह दुनिया भर में सबसे शानदार है. शाही शौक वाले इस करोड़पति की निजी जिंदगी की झलक.

रहन-सहन 76

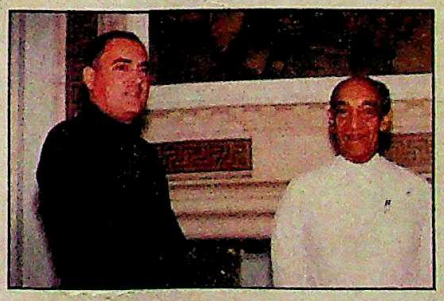

जयवर्द्धने की घेराबंदी

राष्ट्रपति काल के अंतिम वर्ष में जयवर्द्धने भारत-श्रीलंका समझौते के कारण अलग-थलग पड़ते जा रहे हैं. समझौता विरोधियों की बढ़ती संख्या और श्रीलंका में शांति सेना की मौजूदगी के खिलाफ बढ़ते असंतोष के कारण समझौते का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया है.

पास-पड़ोस 62

अगले पन्नों पर

कसौटी 9
राजरंग 11
तेवर 13
हिंदोस्तां हमारा 14
बीता पखवाड़ा 17
आजकल
पंजाब: अंधियारा फिर घिर आया 18
तमस: सांच पर आंच 21
तमिलनाडु: सिंहासन के लिए संघर्ष 22
हरियाणा: दिखावटी बदल 26
मेघालय: जातीय हिंसा का शिकार 27
बोहरा समुदाय: फतवे का खौफ 29
महाराष्ट्र: सपना रहा सपना 30
उत्तर प्रदेश: नए नाते-रिश्ते 31
मध्य प्रदेश: कस्बे की करामात 31
हिमाचल प्रदेश: गैरजरूरी कानून 32
आखिरी बात 33
आंध्र प्रदेश: अदला-बदली 34
केरल: वामपंथी घाटे में 35
दिल्ली: बात का बतंगड़ 35
माया त्यागी कांड: वर्दीवालों पर वज्रपात 36
गुजरात: भंवर में नैया 38
गुजरात: देहगांव में गुरु की देहलीला 39
राज्य-दर्पण 41
खास रपट
राजस्थान: निकले बड़े बेआबरू होकर 42
विशेष लेख
अर्धसैनिक बल: काम के बोझ मे दोहरे 46
आवरण कथा
तंदुरुस्ती की बढ़ती तमन्ना 50
जगबीती
प्रधानमंत्री की यात्रा: स्वीडन के किस्से 58
पास-पड़ोस
श्रीलंका: जयवर्द्धने की घेराबंदी 62
विज्ञान-चर्चा 65
व्यापार चक्र 66
कारोबार
रबी: भरपूर पैदावार के आसार 68
सार्वजनिक उपक्रम: फिर कसौटी पर 70
ठाकरसी घराना: बंटवारे की ओर 73
रहन-सहन
प्राणलाल भोगीलाल: कारों के शौकीन 76
सिनेमा
फिल्मोत्सव: विवाद ही छाया रहा 82
खेलकूद
क्रिकेट: नए खून की लाली 85
अभिव्यक्ति
पटना: तंबू ही तंबू 88
अपराध
उत्तर प्रदेश: सचमुच सती या झूठमूठ 89
जीवन शैली
संगमरमर का प्रचलन 90
विकास
मध्यप्रदेश: लहसुन के जरिये लखपती 93
कला
असम: चलते-फिरते कल्पनालोक 95
प्रचार माध्यम
शैक्षिक टीवी: मंजिल मिलेगी मुश्किल से 97
किताबें 99
परिचित चेहरे 104

आवरण: भवान सिंह

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

क्वालिटी और कीमत का पक्का हिसाब

चेक डिटर्जेन्ट टिकिया की भरोसेमन्द कीमत,
सुरक्षित धुलाई। चाहे रंगीन कपड़े हो या सफेद
कीमत : १२५ ग्राम के २ रूपये (सब कर समेत)

खुद ही चेक कर लीजिये ना!

Shaw Wallace

शॉ वॉलेस का क्वालिटी उत्पादन।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वेरका

देसी घी

100% शुद्ध

Lajesh. Almond.
Kaushal Kumar.

वेरका देसी घी। स्वाद, शुद्धता व उत्तमता में लाजवाब। वेरका के बिना आपका भोजन अधूरा है।

मिल्कफ़ैड का एक उत्तम उत्पादन

MILKFED

दी पंजाब स्टेट कोआप्रेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्ज़ फ़ेडरेशन लिमिटेड, एस० सी० ओ० न० 3015-16 सैक्टर 22-डी, चण्डीगढ़ - 160 022

UNION-2288

OPERATION FLOOD

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

CC-0. Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

क्योंकि कुछ दीवार चाहता है...
रेशमी एहसास और
ताज़गी बरसों तक!

नेरोलॅक ऍक्रिलिक इमल्शन, जिसमें सिलिकोन है, इन खूबियों से भरा है. दीवारें जैसे धुपहली चमक और मख्मली एहसास से ढक जाएं. आसानी से धुलकर निखर आए और चलता ही चला जाए. इसलिए बरसों तक रंगों की ताजगी और शान बरकरार!

'नेरोलॅक गाइड से घरों की बेहतर सजावट' पुस्तिका की अपनी मुफ्त प्रति के लिए यहां लिखिए–
पो. ओ. बॉक्स 9954, बम्बई 400 021.

पोस्टेज के लिए 50 पै. का डाक टिकिट साथ भेजें.

नेरोलॅक

ऍक्रिलिक इमल्शन

जब चाहिए दीवारों पर लाजवाब निखार.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

नेरोलॅक पेण्ट्स
हर रूप, हर रंग में बेहतर!

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इंडिया टुडे
संपूर्ण समाचार पत्रिका

वर्ष: 2, अंक: 7, 1-15 फरवरी 1988

प्रधान संपादक: अरुण पुरी

वरिष्ठ संपादक: प्रभु चावला

लिविंग मीडिया इंडिया प्रा. लि., एफ-14, कंपिटेंट हाउस, कनाट प्लेस, नई दिल्ली के लिए अरुण पुरी द्वारा संपादित और प्रकाशित तथा थॉमसन प्रेस इंडिया लि. फरीदाबाद , हरियाणा में मुद्रित.

संपादकीय कार्यालय:
लिविंग मीडिया इंडिया प्रा. लि., एफ-14/15, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001. फोन: 331 5801-4, टेलेक्स: 31-61245 INTO IN, तार: लिवमीडिया नई दिल्ली.

मुख्य सर्कुलेशन कार्यालय:
इंडिया टुडे सर्कुलेशन मैनेजर, एफ-14, कंपिटेंट हाउस, कनाट प्लेस, मिडल सर्कल, नई दिल्ली-110001. फोन: 3313076-8, टेलेक्स: 31-62634 INTO IN, तार: सर्कुलेट, नई दिल्ली.

मुख्य विज्ञापन कार्यालय:
28 ए और बी, जॉली मेकर चैंबर-2, नरीमन पाइंट, बंबई-400021. फोन: 2026152, 2029326, 2029435, टेलेक्स: 11-5373 THOM IN, तार: लिवमीडिया बंबई.

क्षेत्रीय विज्ञापन कार्यालय:
के-9, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001, फोन: 352378, 323576, 351273, 351323; टेलेक्स: 31-62124 THOM IN, तार: लिवमीडिया, नई दिल्ली ; फागुन चैंबर्स, 26 कमांडर-इन-चीफ रोड, मद्रास-600105. फोन: 477188, 477770, टेलेक्स: 041-6177 INTO IN, तार: लिवमीडिया, मद्रास ; 74/1, सेंट मार्क्स रोड, बंगलूर-560001. फोन: 568448, 579037, 579089, टेलेक्स: 0845-2217 INTO IN, तार: लिवमीडिया, बंगलूर ; 12-सी, एवरेस्ट 46-सी, चौरंगी रोड, कलकत्ता-700016 फोन: 445398, 447726, टेलेक्स: 021-3138 INTO IN, तार: लिवइन-मीडिया, कलकत्ता.

कॉपीराइट 1984 लिविंग मीडिया इंडिया प्रा. लि. विश्व भर में सर्वाधिकार सुरक्षित. किसी भी रूप में सामग्री की नकल प्रतिबंधित. इंडिया टुडे अनिमंत्रित प्रकाशन सामग्री को लौटाने की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता.

नेपाल में 6 रुपए

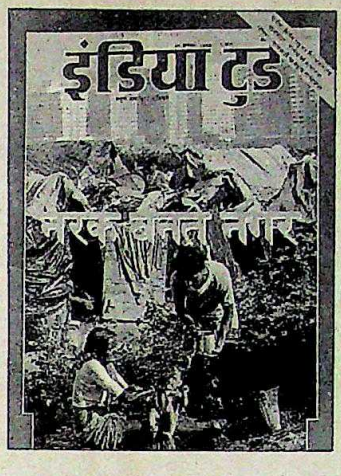

होगा बेड़ा गर्क

आवरण कथा 'खस्ता जिंदगी, बदहाल नगर' (31 जनवरी) पढ़ी. सचमुच आज महानगरों का बुरा हाल हो गया है. नागरिक सेवाओं के चरमरा जाने से लोगों की मानसिक कठिनाइयां भी बढ़ रही हैं. आर्थिक तंगी ने पहले ही उनकी हालत खराब कर रखी है. इससे देश के विकास पर निश्चित रूप से असर पड़ रहा है. सरकार को समय रहते ही कुछ हल निकालना चाहिए वरना बेड़ा गर्क हो सकता है.

—उपदेश कुमार, चंडीगढ़

■ अजीब है हमारी सरकार जिसे महानगरों की दुर्दशा का रत्ती भर भान नहीं है. क्यों नहीं वह पहले से ही ऐसी योजनाएं बनाकर रखती कि शहरों के विकास में जरा भी बाधा न आए. उसे पहले से ही सोचकर रखना चाहिए कि बढ़ती आबादी और उसकी जरूरतों में तालमेल किस तरह बिठाना है.

—राजेश उपाध्याय, नई दिल्ली

■ महानगरों में झोंपड़पट्टियों में रहने वाली आबादी के आंकड़े जानकर हैरानी होती है. 20 से 35 फीसदी आबादी गंदी बस्तियों में रहती है. कहां हैं वे नेता जो रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूल सुविधाएं मुहैया कराने के अक्सर लंबे-चौड़े दावे करते हैं?

—दिनेश अग्रवाल, कैथल (हरियाणा)

■ आखिर सरकार भी क्या करे? महानगरों की आबादी दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रही है. देहात के लोगों के जहां सींग समाते हैं, वहीं घुसे जा रहे हैं. लोग क्यों नहीं सोचते कि उन्हें एक जगह टिककर रोटी कमानी चाहिए?

—बलदेवराज, अलीगढ़ (उ.प्र.)

वंशानुगत राजतंत्र

कसौटी के अंतर्गत 'हावी है परिवारवाद' पढ़कर सचमुच ऐसा लगता है कि आज लोकतंत्र की आड़ में वंशानुगत राजतंत्र चल रहा है— एक ऐसा राजतंत्र जिसके दरबार में गरीबों की ऊंची आवाज नहीं सुनाई पड़ती. संभवत: इस खतरनाक पद्धति के लिए जनता भी काफी हद तक जिम्मेदार है.

—दिलीप जायसवाल, धनबाद (बिहार)

बड़ा नुकसान

खास रपट 'जल्दबाजी का महंगा खामियाजा' (31 जनवरी) पढ़ी. थोड़ी-सी जल्दबाजी करने से एक साधारण लड़ाई बड़ी लड़ाई में बदल गई है. इससे भारत को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है और न सिर्फ बदनामी हो रही है बल्कि हमारे जवान भी शहीद हो रहे हैं.

—घनश्याम जोशी, तेजरासर (राज.)

■ सरकार अपने देश में फैले आतंकवाद पर तो काबू नहीं पा सकी. पर श्रीलंका में सेना भेजकर वहां के हालात पर काबू पा रही है. ठीक है कि वहां के तमिल उग्रवादी दंगे-फसाद करते हैं पर यहां जो रोज एक न एक आदमी उग्रवादियों की गोली का शिकार हो रहा है, उसका कोई महत्व नहीं?

—समीर बतरा, राजपुरा (पंजाब)

प्रधानमंत्री की फिजूलखर्ची

'निर्जन टापू पर निश्चिंत पड़ाव' (31 जनवरी) पढ़कर आश्चर्य हुआ कि लाख आलोचनाओं के बावजूद राजीव ने इतनी बेफिक्री से पिकनिक मनाई. लगता है अब राजीव के राजनैतिक जीवन का अंतिम पड़ाव पड़ने ही वाला है. क्या ही अच्छा होता यदि बाढ़ और सूखे की मार से बेहाल देश की बागडोर थामने वाला व्यक्ति मितव्ययी होता.

—दुर्गेशनंदन सिंह, बेगूसराय (बिहार)

■ राजीव गांधी के परिवार सहित छुट्टियां मनाने में आए खर्च व दूसरी बातों की कितनी ही आलोचना क्यों न हो पर एक बात साफ है कि 'बड़े लोगों' की ऐसी यात्राओं से पर्यटन विकास को बढ़ावा मिलने के साथ ही जनसाधारण में पर्यावरण के प्रति लगाव का भाव भी बढ़ेगा और प्राकृतिक सौंदर्य के संरक्षण का भी.

—बृजेश विजयवर्गीय, कोटा (राज.)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इधर भी ध्यान दें

'परंपरा की व्यथा कथा' (31 जनवरी) पढ़कर मन व्यथित हो उठा. बांछड़ा जाति की बेटियां जीते जी नरक भोग रही हैं. सती प्रथा और दहेज प्रथा के खिलाफ तो महिलाएं आवाज बुलंद करती हैं पर इन सामाजिक कुरीतियों की ओर ध्यान देने के लिए न तो उनके पास समय है और न ही सरकार को फुरसत है.

—**सुनील कुमार सिंह,** पटना (बिहार)

■ यह मजबूरी न केवल बांछड़ा जाति की बेटियों की है बल्कि देश के कई राज्यों में गरीब व पिछड़ी जातियों की लड़कियों की भी लगभग यही मजबूरी है. देश का दुर्भाग्य ही है कि आर्थिक विपन्नता के दुष्चक्र में फंसकर पेट भराई के लिए स्त्रियां वेश्यावृत्ति जैसे नारकीय धंधे अपनाने को मजबूर हो रही हैं

—**चेतन चौहान,** जोधपुर (राज.)

यह आधुनिकता नहीं

विशेष लेख 'पुराने शहर का नया रंग' (31 जनवरी) में आधुनिकता से दूसरा ही अर्थ निकलता है. आधुनिकता जीस, शराब और डिस्को से नहीं आती बल्कि विचारों से आती है. जींस या डिस्को इसके बहुत ही छोटे हिस्से हैं. विचारों में अगर बदलाव होगा तभी जीवन आधुनिकता की ओर अग्रसर होगा, 'फास्ट फूड' से नहीं. जीवन शैली नहीं जीवन मूल्य बदलना चाहिए.

—**कपिल मिश्र,** होशंगाबाद (म.प्र.)

डूबते सूरज का अक्स

आवरण कथा 'विडंबनाओं का वर्ष' (15 जनवरी) पढ़ा. वर्ष 1987 के डूबते सूरज का बहुआयामी नक्शा बेहद खूबसूरती से दिखाया है आपने. यह भी विडंबना ही है कि एक रुखसत होते साल का विदाई गीत हमें 'विडंबनाओं का वर्ष' के रूप में गाना पड़ा. दिलीप बॉब ने हमारी सूखती संवेदनाओं और मरते मूल्यों का अक्स ईमानदारी और सावधानी से खींचा है.

—**प्रबोध गोविल,** कोल्हापुर (महाराष्ट्र)

■ बीता साल ठीक नहीं रहा. एक ओर सूखे की मार तो दूसरी तरफ राजनीति में भारी उथलपुथल. राजीव की छवि को जहां भारत में थोड़ा धक्का लगा, वहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छवि में निखार भी आया. सूखे के लिए यह साल सदा याद रहेगा.

—**प्रवीण चंद्र सोनी,** बेलारी (कर्नाटक)

अजीब अपराध

'बच्चे की बलि' (15 जनवरी) पढ़ी. अजीब है यह दुनिया. तांत्रिक के कहने पर खजाना पाने के लिए बच्चे की हत्या एक भयंकर अपराध है. पैसे की भूख में अपनी पत्नी और बच्चे की भी हत्या की जा सकती है?

—**राजेश कुमार पाठक,** फुसरो (बिहार)

■ शरणार्थी चाहे तमिल हों ('शरणार्थी बने रहेंगे', 15 जनवरी) या चकमा, वे उन समस्याओं को और बढ़ाएंगे जिनसे हमारी सरकार पहले ही लड़ रही है. सरकार को चाहिए कि वह उनसे संबंधित देश से शीघ्र बात करके उन्हें वापस भेजे.

—**अखिल जैन,** कानपुर (उ.प्र.)

दमन से उपजा आंदोलन

'खुखरियों की खूंरेजी' (15 जनवरी) पढ़ा. दार्जिलिंग में उत्पन्न हिंसा प्रशासनिक दमन के विरुद्ध जनाक्रोश है. गोरखालैंड आंदोलन शुरू से शांतिपूर्ण था, लेकिन पश्चिम बंगाल की साम्यवादी सरकार की दमनकारी नीति के कारण गोरखाओं को आत्मरक्षा के लिए हिंसा पर मजबूर होना पड़ा.

—**गणेश क्षेत्री,** कलिम्पोंग (प. बंगाल)

■ यह लेख एकतरफा है. इसमें आंदोलनकारियों के कारनामे तो हैं लेकिन अर्द्ध-सैनिक बलों द्वारा बेगुनाहों पर अत्याचार की घटनाएं नहीं दी गई हैं.

—**दे.प्र. चार्मलिंग,** दार्जिलिंग (प. बंगाल)

लाजवाब तेवर

'तेवर' (15 जनवरी) में लोगों के विचार पढ़े. ऐसा लगा कि राज्य स्तर के प्रतिष्ठित नेता एवं व्यक्ति कितनी ओछी बातों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के लिए करते हैं. लगता है वे उनकी प्रधानमंत्री के रूप में कम, एक व्यक्ति के रूप में अधिक आलोचना करते हैं.

—**अमरेंद्र नाथ उपाध्याय,** गोरखपुर (उ.प्र.)

■ व्यंग्य लेखक शरद जोशी का यह कथन—ठक्कर नटराजन आयोग की रिपोर्ट से बेहतर हास्य तो मैं ही लिख सकता हूं—सर्वश्रेष्ठ लगा. उपरोक्त रिपोर्ट के संबंध में शरद जोशी के विचार बुद्धिजीवियों के विचारों को ही प्रतिबिंबित करते हैं.

—**सुशील कुमार त्यागी,** हरिद्वार (उ.प्र.)

■ 'तेवर' पढ़कर मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि राजीव गांधी देश के अब तक के सबसे कमजोर एवं अनुभवहीन प्रधानमंत्री साबित हुए हैं और होते जा रहे हैं.

—**घनश्याम राठौड़,** धनबाद (बिहार)

कमी खलेगी

'मंझधार में राजनीति' (15 जनवरी) पढ़कर लगा कि एमजीआर सचमुच एक मसीहा थे. उनकी कमी खलेगी. जानकी रामचंद्रन इस रिक्त स्थान की पूर्ति कर पाएंगी या नहीं यह तो समय ही बताएगा.

—**जितेंद्र गगनीजा,** सिरसा (हरियाणा)

■ एमजीआर ने सिनेमा की अपनी लोकप्रिय छवि राजनीति में भी बरकरार रखी. उनके अंतिम संस्कार के समय उमड़ पड़ी भीड़ और लोगों की शोकाकुल अवस्था को देखकर यही लगता है कि वे सचमुच एक चमत्कारी जननायक ही थे. 'कसौटी' के अंतर्गत 'लुटाने का अर्थशास्त्र' पढ़ा. विपक्षी सरकार को गिराकर अपनी सरकार बनाना ही कर्ज मेलों का मकसद है.

—**प्रताप सिंह हजारी,** पुणे (महाराष्ट्र)

■ करिश्माई व्यक्तित्व वाले एमजीआर के निधन के बाद तमिलनाडु की राजनीति भविष्य में किस ओर करवट लेगी, अभी से ठीक-ठीक कहना असंभव है. इंडिया टुडे ने फिर भी सही दिशा में पहुंचने का अच्छा प्रयास किया है. 'विडंबनाओं का वर्ष 1987' की सचित्र झलकियों के कारण यह अंक संग्रहणीय बन गया है.

—**मुकेश गुप्ता,** गाजियाबाद (उ.प्र.)

बवंडर के पहले शांति

'संगठित होते आतंकवादी' (15 जनवरी) पढ़कर लगा कि राजनीतिक जिस शांति और विजय का दावा कर रहे हैं वह महज आतंक के दबने का प्रतीक नहीं है अपितु भविष्य में और अधिक भयानक बवंडर का संकेत है जो पुनः पंजाब को अस्थिर कर देगा.

—**सुरेश कुमार वर्मा,** अंबाला (हरियाणा)

■ जिस राज्य में पुलिस अधिकारी तक सुरक्षित नहीं हैं वहां की आम जनता दहशत और आतंक के बीच कैसे जीती होगी, सहज

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and e

"३ कमाल वाला टूथपेस्ट क्यों हमने भी अपनाया"

"मानिए या ना मानिए, पर मैंने तो सचमुच अपना टूथपेस्ट बदल डाला है! अब मैंने अपनाया है **लौंग, फ्लोराइड** और **मिन्ट** के ३ कमाल वाला प्रूडेन्ट. है मेल इतना अच्छा, मानों दांतों का साथी सबसे सच्चा!
अनुराधा ने एक और खूबी पायी – प्रूडेन्ट की सॉफ्ट-स्क्वीज़ ट्यूब! सदा रहे साफ-सुथरी. ऐसी खूबी और किसी टूथपेस्ट में कहां है!"

मुफ्त! दांतों की देखभाल के लिए रंगीन पुस्तिका. सीमित संख्या में.
लिखिए : पारले प्रॉडक्ट्स प्रा. लि., निर्लोन हाउस, २५४-बी, डॉ. ए.बी. रोड, बम्बई ४०० ०२५.

प्रूडेन्ट में हैं कमाल ३, दांतों के लिए बेहतरीन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

पारले

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कल्पनीय है. अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित दो पुलिस अधिकारी बराड़ और गिल की हत्या ने स्पष्ट कर दिया है कि पंजाब में आतंकवादी फिर से संगठित हो चुके हैं.

—**प्रणव कुमार मिश्र,** जमालपुर (बिहार)

■ जब तक आतंकवादियों को विदेशी सहायता मिलती रहेगी, पंजाब में आतंकवाद से निबटना मुश्किल है. भारत सरकार को चाहिए कि वह पाकिस्तान से इस बारे में बात करे.

—**रघुराज सिंह सिसोदिया,** मंदसौर (म.प्र.)

■ रिपोर्ट पढ़कर लगा कि पंजाब में जैसे सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है. सरकार कुर्सी के उन भूखों को बेनकाब करे जो धर्म की आड़ में विदेशियों के इशारे पर पंजाब की पवित्र भूमि को निर्दोषों के खून से रंग रहे हैं.

—**सेठपाल चित्तौड़,** खदरी (हरियाणा)

■ पंजाब की सरजमीं पर जिस तरह से आतंकवाद का प्रकोप बढ़ता जा रहा है उसमें पंजाब का हर नागरिक अपनी सुरक्षा के प्रति आशंकित है. पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की रिहाई के बाद आतंकवादियों को नए सिरे से प्रोत्साहन मिला है. जब तक पंजाब में सांप्रदायिक पार्टियां अस्तित्व में रहेंगी, तब तक धर्मनिरपेक्ष राजनीति का उदय नहीं हो सकता. आतंकवाद समाप्त करने के लिए पंजाब की जनता का विश्वास पाना जरूरी है.

—**सतीश उपाध्याय,** मनेंद्रगढ़ (म.प्र.)

खतरनाक प्रवृत्ति

'महिमामंडित आतंकवाद' (15 जनवरी) पढ़ा. उग्रवादियों ने नई रणनीति अपना ली है. जो उग्रवादी पुलिस मुठभेड़ में भाग गया है उसे शहीद का दर्जा देकर उसके नाम से सीमावर्ती क्षेत्रों में स्मारक आदि स्थापित करना सूरज की रोशनी में शासन तंत्र को बेवकूफ बनाने का प्रयत्न है. सरकार को चाहिए कि वह उग्रवादियों की इन कार्रवाइयों पर प्रतिबंध लगाए. बाद में लकीर पीटने से कुछ नहीं होगा.

—**गुरुदेव सिंह भाटिया,** सेंधवा (म.प्र.)

■ पंजाब में लोग आतंकवादियों और हत्यारों को महिमामंडित करते जा रहे हैं. सरकार ने जहां एक ओर सती को महिमामंडित करने वालों को दंड दिलाने का कानून बनाकर सराहनीय कार्य किया है, वहीं वह इस ओर से चुप्पी क्यों साधे है?

—**महेश चंद शर्मा,** मेरठ (उ.प्र.)

■ आतंकवाद की इस बीमारी को इस सीमा तक लाने का दोष निश्चय ही मौजूदा स्वार्थपूर्ण राजनीति को दिया जा सकता है. अब नए तरीके से आतंक फैलाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है. इस स्थिति के विस्फोटक होने से पूर्व ही उचित और सख्त कदम उठाना बेहद आवश्यक है.

—**राजेश झांब,** मंदसौर (म.प्र.)

■ यह अत्यंत चिंताजनक सत्य है कि पंजाब में कुछ जगहों पर उग्रवाद को महिमामंडित किया जा रहा है. यह गंभीर रोग अगर तुरंत समाप्त नहीं किया गया तो इसके भयानक परिणाम होंगे. हमें ऐसे पूजाघरों, गुरुद्वारों के निर्माण को राष्ट्रद्रोह जैसे अपराध की श्रेणी में रखकर दोषियों को दंडित करना चाहिए.

—**रामकुमार तेलंडिया,** नई दिल्ली

तुगलक के अवतार

'सैर की सनक' (15 जनवरी) पढ़ने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ताकतवर नेताओं की सुविधा के लिए लाखों खर्च किए जा सकते हैं. आज राजस्थान की अधिकांश जनता सूखे से त्रस्त है. इससे उबरने के लिए उन्हें केवल आश्वासनों की बाढ़ में डुबकियां लगानी पड़ रही हैं.

—**ओमप्रकाश,** झुंझुनू (राजस्थान)

■ लगता है राजीव गांधी तथा मुहम्मद बिन तुगलक की विचारधारा में कोई फर्क नहीं है. सत्ता के मद में चूर राजीव इतिहास पुरुष बनना चाहते हैं. संसार के सबसे गरीब देशों में एक हमारे देश की निरीह जनता के धन का विवेकहीन दुरुपयोग क्या हमें अंधकारमय भविष्य की ओर नहीं ले जा रहा.

—**परमेश्वर गुप्त,** नागपुर (महाराष्ट्र)

■ राजीव सरकार 21वीं सदी में तो क्या ले जाएगी, 21 महीने भी और टिक पाए तो कमाल की बात होगी. अभयारण्य में, जोकि देश के अधिकतम सूखापीड़ित प्रदेश का इलाका है, 50 लाख रुपए इसलिए खर्च कर दिए गए ताकि राजीव गांधी यह विचार कर सकें कि फिजूलखर्ची कैसे रोकी जाए. यह पैसा अगर राहत कार्य पर खर्च किया गया होता तो देश के करोड़ों गरीबों और मेहनतकशों को फायदा होता.

—**अमित कुमार,** चंडीगढ़

■ राजीव गांधी के बाथरूम की सजावट के बारे में पढ़ते ही मुझे लगा कि राजीव देश की ओर ध्यान नहीं दे रहे. ऐसा प्रधानमंत्री किस काम का जो भारत की जनता का हित नहीं सिर्फ अपना हित जानता है.

—**मुन्ना लाल,** दमोह (म.प्र.)

■ लेख पढ़कर लगा जैसे राजीव की समझ का दिवाला ही निकल गया है. अभी तक राजीव को देश के लोगों की भावनाओं की समझ नहीं है. धन्य है भारत जो ऐसे तुगलकी रवैये वाले प्रधानमंत्री को झेल रहा है.

—**प्रकाशचंद्र झा,** पीरपैंती (बिहार)

■ पता चल गया कि राजीव और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य कितने बुद्धिमान हैं, जो यह विचार करने गए थे कि फिजूलखर्ची में कैसे कमी की जाए.

—**रोहित तिवारी,** भोपाल (म.प्र.)

गरीबी का मजाक

'शानो-शौकत भरी शादी' (15 जनवरी) पढ़ा. लगता है देश के लोग गरीबी रेखा पार कर गए हैं तभी चित्रांगदा की शादी में 30 करोड़ तथा शानू हिंदुजा की शादी में 50 करोड़ रुपए खर्च किए गए. यह गरीबी का मजाक है. ऐसे अवसर पर केंद्रीय मंत्री व समाजवाद के अग्रणी भी फोटो खिंचवाने पहुंचकर अपना बड़प्पन साबित करने में शर्म नहीं खाते.

—**मुहम्मद ईसा,** इलाहाबाद (उ.प्र.)

■ सरकार को चाहिए कि वह आयकर की तरह व्ययकर भी तय करे. तभी यह विडंबना दूर होगी कि एक ओर तो शराब की नदियां बहें व दूसरी ओर तीन दिन में एक बार राशनिंग से पानी मिले.

—**श्याम ज्वालामुखी,** भीलवाड़ा (राज.)

■ कौन कह सकता है कि जहां दो दिलों के बंधन के लिए करोड़ों रुपए की बलि चढ़ा दी जाती हो उस देश की 60 प्रतिशत जनता गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रही है.

—**सब्बु चौहान,** पाली-मारवाड़ (राज.)

■ हिंदुजा और सिंधिया परिवार के शादी-विवाह की सर्वत्र आलोचना हो रही है लेकिन ऐसे धनवान परिवार अगर इस तरह पैसा नहीं खर्च करेंगे तो इनके खजानों में रखा अरबों रुपया ब्लॉक होकर रह जाएगा. इन शादियों से बहुतों को काम मिला है.

—**माधवी मनोज,** भोपाल (म.प्र.)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कसौटी

सत्ता का सम्मोहन

शांति निकेतन के छात्रों को राजीव गांधी ने एक 'महत्वपूर्ण' सलाह दी है—'अखबार मत पढ़िए. वे सरासर झूठ छापते हैं.' बातचीत करने वाले किसी से उन्होंने कहा कि वे अब सख्त हो गए हैं. और किसी पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि नए वर्ष पर आपने क्या संकल्प किया है तो उनका जवाब था—प्रेस को कतई गंभीरता से न लेने का संकल्प.

सत्ता का कुछ रंगढंग ही ऐसा है कि सत्ता में बैठा व्यक्ति दिन-ब-दिन असहिष्णु, आलोचनाओं के प्रति लापरवाह होता जाता है. असुविधाजनक विचारों व सूचनाओं के लिए वह आंख-कान बंद करने लगता है. यह देश के अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों के लिए तो सही है ही, कई मुख्यमंत्रियों और दूसरे छोटे-मोटे पदों पर बैठे लोगों के लिए भी उपयुक्त है. राजीव गांधी कोई अपवाद नहीं हैं.

रेखाचित्र: अजीत नाइनन

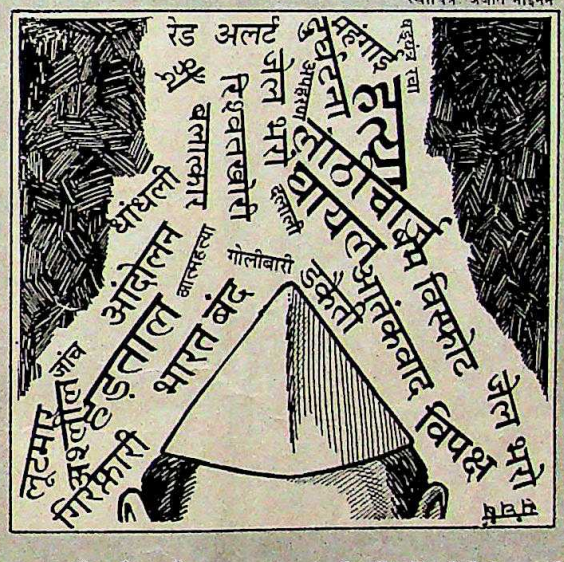

अमिताभ बच्चन को अपने साथ छुट्टी मनाने के लिए लक्षद्वीप ले जाना एक तरह की बेशर्मी ही तो है. यह तो मानो पूरे देश को यह जताना है कि अमिताभ पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं या उनके भाई के खिलाफ जो कथित जांच चल रही है उन सबको तो राजीव गांधी ठेंगे पर रखते हैं और एक बार फिर नौसैनिक सुविधाओं का गलत इस्तेमाल किया जाता है. एक अपेक्षाकृत शांत राज्य के मुख्यमंत्री की छुट्टी कर दी जाती है क्योंकि उसने वही गलती की जो आंध्र के मुख्यमंत्री टी. अंजैया ने की थी, और क्योंकि 'दरबार' के किसी खासमखास की भी यही तमन्ना थी. फिर बोफोर्स के मामले पर एक तरह की आत्मतुष्टि और अपमानजनक लापरवाही का भाव है जो कि अनुमान से ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है. ऐसी बेशर्मियों की सूची और भी लंबी की जा सकती है. लेकिन सबसे बड़ा कांटा तो है प्रेस. काश खुराफाती छायाकार न होते जो छुट्टियां मनाकर लौट रहे फिल्मस्टारों के फोटो न खींचते. तो जीवन कितना सहज होता!

चाटुकारिता की राजनैतिक संस्कृति में, जहां चमचों और जीहुजूरी करने वालों से बच पाना असंभव-सा ही है, सत्ता में बैठे व्यक्ति के क्रूर और संवेदनशून्य होने का खतरा कहीं ज्यादा होता है. सम्मोहित चौकड़ी से बाहर की वास्तविकताओं से उसका कट जाना नितांत अवश्यंभावी है. ऐसे में आलोचनाओं की आंच से बचे रहना बड़ा सुखदायी लगता है. और यही संकट का संकेत है.

सत्ता के नशे के शिकार होने वाले अकेले राजीव गांधी ही नहीं हैं. इंदिरा गांधी भी ऐसों में थीं. उन्होंने तो खुद को देश का पर्याय ही घोषित करवा दिया था. उनकी आलोचना यानी राष्ट्रद्रोह! और संजय गांधी के बारे में यह कहा गया कि उनकी आलोचना तो इसलिए हो रही है क्योंकि बड़े व्यापारी नहीं चाहते थे कि कोई युवक अपने उद्यम में सफल हो. और भी उदाहरण हैं ऐसे. नंदमूरि तारक रामराव अपने लंबे सफल फिल्मी जीवन में मिली प्रशंसाओं के इतने अभ्यस्त हो गए कि राजनीतिक के रूप में वे आलोचनाओं से लापरवाह होकर अपने बेटे-दामादों को आगे बढ़ाने में ही लगे हैं.

इन तमाम उदाहरणों के मूल में यह मनोभाव दिखता है—मैं जो सोचता हूं वही ठीक है, देश का भला कैसे होगा यह मैं ही जानता हूं, मेरे बिना तो सरकार चल ही नहीं सकती, और फिर मेरी आलोचना करने वाले ये लोग हैं कौन? क्या ये अज्ञानी और कुटिल लोग नहीं हैं? यह मनोभाव सत्ता के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति का ही होता है जो हकीकतों से जुड़ पाने या सत्ता के नशे में भी अपने होशोहवास कायम रख पाने में असफल रहता है.

आलोचनाओं के प्रति लापरवाही राजनीति में बने रहने के लिए चमड़ी मोटी करने जैसी बात ही है. या फिर यह एक सोचा-समझा गणित हो कि मध्यवर्गीय धारणाओं से कुछ नहीं बिगड़ता, वोट बैंक तो कोई और वर्ग है. लेकिन यह किसी बंद दिमाग की धारणा भी हो सकती है कि आलोचक हमेशा विरोधी ही होता है. आलोचना को अगर व्यक्तिगत आक्षेप माना जाता है तो उसके जवाब में मुद्रा सुरक्षात्मक हो जाती है. तब गलतियों को समझने या सुधारने की कोशिश नहीं की जाती इसके आगे तो बस यही होता है कि अगर किसी साथी की भी आलोचना हो तो उसे भी अपने ऊपर ही हमला मान लिया जाता है. इसी मनःस्थिति में कोई नेहरू किसी कृष्ण मेनन को साथ लगाए रहता है और नुकसान देश को भुगतना पड़ता है.

इस सबका मतलब यह नहीं है कि नेता को हर विचार या हर आलोचना के आगे दंडवत मुद्रा में ही आ जाना चाहिए. वास्तव में राजीव जब सत्ता में आए थे तो शुरू-शुरू में उन्होंने श्रीमती गांधी की शैली से हटकर खुलेपन की नीति से राजनीति में एक नई लहर पैदा की थी. वे मानो लोकप्रियता के सभी प्रतिमान तोड़ने को तैयार दिख रहे थे. हर पड़ोसी को खुश करने और एक के बाद दूसरे समझौते करने को बेताब! लेकिन लोकप्रियता उनकी तेजी से गिरी भी. अब एक मुश्किल और यातनापूर्ण दौर से गुजरने के बाद बचे रह पाने से जो आत्मविश्वास जमा है उससे एक तरह की क्रूरता और हेकड़ी पनपी है. और यही शायद अन्य सभी बातों से ज्यादा आत्मघाती हो सकती है.

वैसे सच तो यह है कि सत्ता मद में आकंठ डूबे व्यक्ति से यह अपेक्षा कुछ ज्यादा ही होती है कि वह आलोचनाओं का आदर करेगा, या चाटुकारों को परे रखेगा. समय की नब्ज को पहचानने के बजाय बुरी खबर लाने वाले संदेशवाहक को बुरा-भला कहना कुछ देर के लिए भले ही आसान लगता हो लेकिन क्या पता आज वह संदेशवाहक प्रेस है तो कल को वोटर न हो जाए.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जो प्रमुख दू-व्हीलर निर्माताओं की पसंद है
आप भी वही टायर्स चुनिए

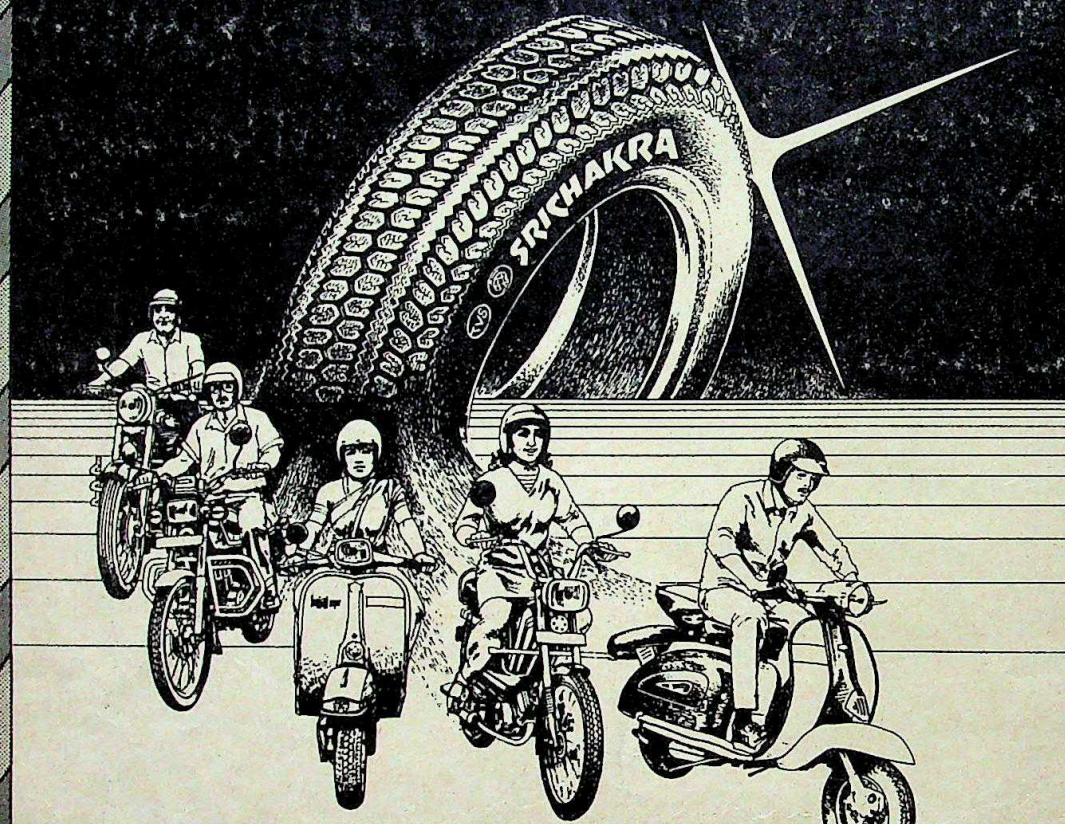

TVS
SRICHAKRA

मौलिक साधन पसंद करने वाले भारत के सभी प्रमुख दू-व्हीलरों के लिए. ज़्यादा सुरक्षा और भरोसेमंद पकड़ के लिए मज़बूत बनाए गए.

सचमुच अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टायर. श्रीचक्रा बनाने वाले हैं टी वी एस – 'ऑटो एन्सीलियरीज़' में जाना-माना एक विश्वसनीय नाम.

भारत के ऊबड़-खाबड़ रास्तों के लिए ख़ासतौर से बनाए गए. श्रीचक्रा टायर ऐसी अनोखी खूबियों से बने हैं जो आपको दें उत्तम कार्यकुशलता और ज़्यादा माइलेज. साथ ही रीट्रेडिंग के लिए इसमें कमाल की गुंजाइश है.

इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सभी प्रमुख दू-व्हीलर निर्माता टी वी एस श्रीचक्रा ही पसंद करते हैं.

TVS SRICHAKRA TYRES

STU/543/HN

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दोस्ती का हाथ

● लगता है विरोधियों के प्रति प्रधानमंत्री राजीव गांधी का रवैया कुछ नरम हुआ है. वैसे इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जब वे बैठे थे तो उनकी कार्यशैली सुलह-समझौते वाली थी. और कई फैसलों में वे विरोध पक्ष को साथ लेकर चलने की कोशिश

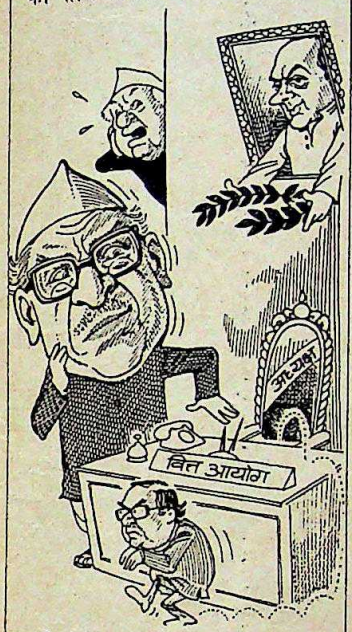

करते देखे गए थे. लेकिन बाद में कुछ-कुछ वे अपनी मां के पदचिन्हों पर चलने का आभास देने लगे थे. लेकिन इधर अब फिर से वे कुछ विपक्षी नेताओं की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं. उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा अपने प्रखर आलोचक लोकदल (ब) के अध्यक्ष हेमवती नंदन बहुगुणा की ओर मुड़ा है.

भरोसेमंद इंकाई सूत्रों के मुताबिक बहुगुणा को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाने का न्यौता देने पर गंभीरता से विचार हो रहा है. यह आयोग केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे के बारे में सुझाव देता है. इस समय कांग्रेसी सांसद एन.के.पी. साल्वे इस आयोग के अध्यक्ष हैं.

कांग्रेस से गए नेताओं को वापस पार्टी में लाने की यह पुरानी रणनीति है. यशवंतराव चव्हाण जब कांग्रेस (स) में थे, तो उन्हें सत्तारूढ़ दल में लाने के लिए वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था. पर ऐसी तमाम योजनाओं में जोखिम और समस्याएं तो रहती ही हैं. बहुगुणा को 'घर लौटाने' और वित्त आयोग के अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाने से गढ़वाल पर्वतीय क्षेत्र में उनके प्रतिद्वंद्वी, ब्राह्मण भाई वित्तमंत्री नारायण दत्त तिवारी नाराज हो सकते हैं. तिवारी खेमे के लोग इस सुझाव के विरोध में अभी से जुट गए हैं.

गुमनामी मंजूर नहीं

● बरखास्त किए गए विदेश सचिव यों ही गुम नहीं हो जाते, कम-से-कम ए.पी. वेंकटेश्वरन जैसे धाकड़ कूटनीतिज्ञ तो नहीं ही. पिछले वर्ष राजीव गांधी ने उनकी छुट्टी कर देने की अपमानजनक घोषणा एक संवाददाता सम्मेलन में की थी. इस हादसे पर हुए भीषण शोरशराबे के बाद वेंकटेश्वरन कुछ दिनों के लिए तो जैसे पृष्ठभूमि में चले गए थे. लेकिन कुछ ही दिनों बाद वे हिंदुजा फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में अवतरित हुए. यह फाउंडेशन करोड़ों के दान कोष से कई परियोजनाएं चलाता है.

लेकिन अब वे फिर कोई नया धमाका करने वाले हैं. हिंदुजा फाउंडेशन को छोड़ अब वे फिर से विदेश नीति से जुड़ने वाले हैं लेकिन सरकारी तौर पर नहीं. वे भारत में

सूत्री कार्टून: अजीत नाइनन

पहली बार विदेशी मामलों से संबंधित एक 'थिंक टैंक' (विद्वत् मंडली) का गठन करने वाले हैं. यह मंडली सेमिनार, भाषणमालाएं आयोजित करेगी, किताबें और दस्तावेज वगैरह प्रकाशित कराएगी और अपने इन कार्यक्रमों में विदेश नीति से जुड़ी बड़ी हस्तियों को शरीक करेगी. इस पूरी योजना पर एक करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है. सूत्रों के अनुसार वेंकटेश्वरन अब तक 50 लाख रुपए जुटा चुके हैं.

बच गए जाते-जाते

● अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की पिछली बैठक में पार्टी के कुछ नेताओं पर गाज गिरने जा रही थी. निशाना थे दो इंका महा-

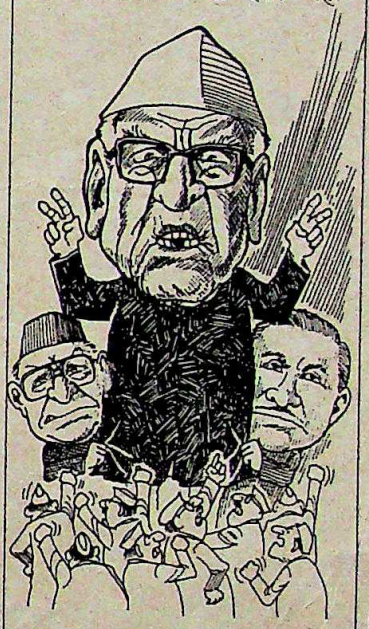

सचिव— बिहार के रामरतन राम और उत्तर प्रदेश के नरेशचंद्र चतुर्वेदी. समिति की बैठक में गरमागरम बहस के दौरान इन दोनों को हटाने की मांग करने वाले सदस्यों का कहना था कि प्रेस के सामने मुंह न खोलने की आलाकमान की सख्त ताकीद के बावजूद ये दोनों महासचिव अखबारवालों से ऊटपटांग बतियाते रहते हैं. और इस कारण पार्टी की बडी भद होती है.

इस आरोप के जवाब में इन महासचिवों का कहना था कि विभिन्न राज्यों के इंकाई मुख्यमंत्रियों के खिलाफ असंतोष की आग सुलगाने के लिए उन्होंने जिन पार्टी वालों की खिंचाई की थी, वे ही निहित स्वार्थी तत्व उन पर इस तरह के बेबुनियाद आरोप मढ़ रहे हैं. उनके इस स्पष्टीकरण के बावजूद ज्यादातर नेताओं की राय थी कि दोनों की छुट्टी ही कर दी जाए. पर पार्टी के संगठनात्मक मामलों के प्रभारी, बुजुर्ग नेता उमाशंकर दीक्षित ने उन्हें बचा लिया. दीक्षित ने अपने सहयोगियों से कहा कि रामरतन व चतुर्वेदी को उनके पदों से हटाने से पार्टी की ही बदनामी होगी क्योंकि अभी दो महीने पहले ही तो बड़े तामझाम से उन्हें पार्टी के बड़े पदों पर बिठाया गया था. उनका तर्क था कि इन दोनों को काबिलियत साबित करने का मौका दिया जाना चाहिए.

आखिरकार पार्टी के नेताओं ने इस बुजुर्ग नेता की यह सलाह मान ली. इसकी एक वजह शायद यह भी हो सकती है कि दीक्षित आजकल प्रधानमंत्री के बहुत करीबी हैं.

फैसलों की असलियत

● पिछले साल दिसंबर में राजस्थान के सरिस्का अभयारण्य में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की 'विशेष' बैठक क्या प्रचार पाने के राजीव सरकार के एक और अभियान का ही हिस्सा थी?

बाघ अभयारण्य में हुई बैठक के बाद किए गए फैसलों में से एक को यदि पैमाना माना जाए तब तो यही सच लगता है. वह अहम ऐलान यह था कि सरकार के गरीबी हटाने और गांवों का विकास करने के कार्यक्रमों में नई जान फूंकी जाएगी. पर नई जान डालने का महती काम कैसे चल रहा है, यह कहीं दिखाई

नहीं देता. बैठक के तुरंत बाद ही चालू वित्तीय साल के लिए ग्रामीण विकास के बजट में 126 करोड़ की कटौती कर दी गई है और कुछ ऐसी नई शर्तें भी रख दी गई हैं, जिनकी वजह से राज्य सरकारों को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए केंद्र सरकार से पैसा लेने में कई दिक्कतें पेश आएंगी.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

फायदे जरा तौल कर देखीए !

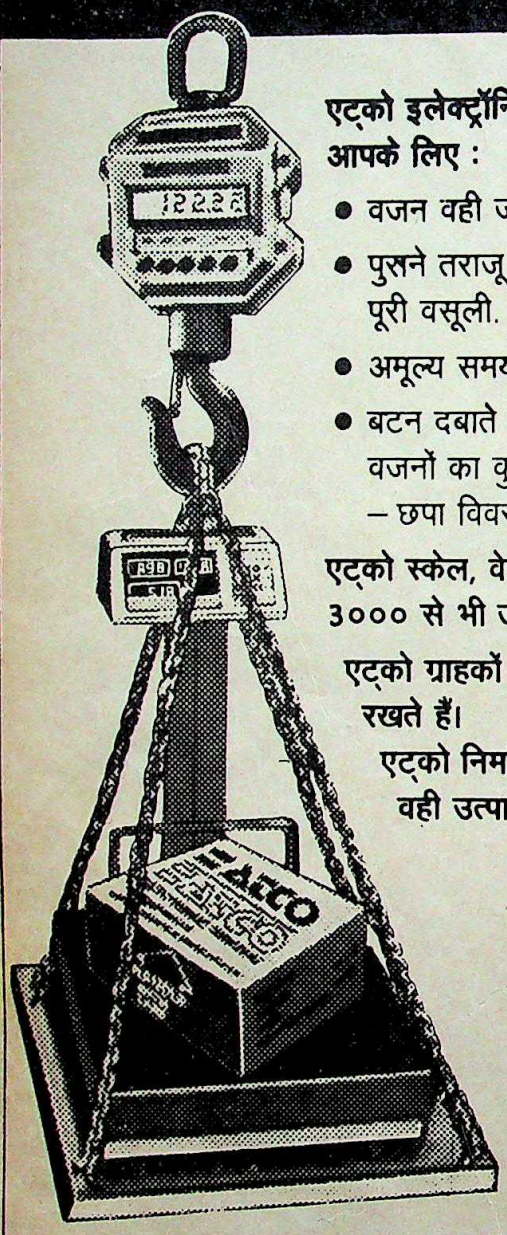

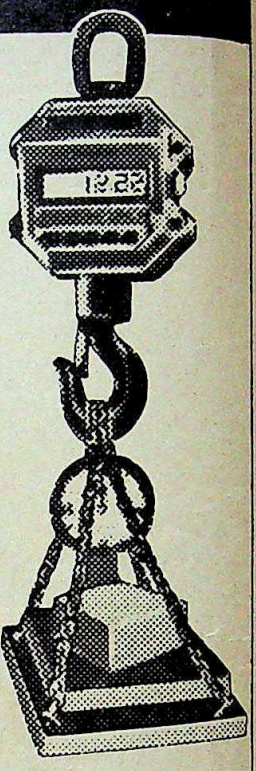

एट्को इलेक्ट्रॉनिक वेइंग सिस्टम से खास फायदे आपके लिए :

- वजन वही जो सही.
- पुराने तराजू को विदा कहने से पहले ही कीमत की पूरी वसूली.
- अमूल्य समय और जगह की बचत.
- बटन दबाते ही मिलेंगे – सही वजन – वजनों का जोड़ – वजनों का कुल जोड़ – भागों की गिनती – पैकिंग का वजन – छपा विवरण.

एट्को स्केल, वेइंग सिस्टम में एक विश्वसनीय नाम है जो 3000 से भी ज्यादा जाने-माने संस्थान इस्तेमाल करते हैं।

एट्को ग्राहकों की सेवा और संतुष्टि का पूरा-पूरा ध्यान रखते हैं।

एट्को निर्माता सही माप के लिए वचनबद्ध हैं ताकि आपको वही उत्पादन मिले जो हर स्तर व दृष्टि से सही हो.

एट्को मार्केटिंग प्रा. लि.
104, क्रिएटिव इंडस्ट्रियल सेंटर,
72, एन. एम. जोशी मार्ग, सीताराम मिल कंपाउंड,
बम्बई 400 011.
फोन : 896472/896848/398934/397814/372665
टेलेक्स : 011 73944 ATCO IN. ग्राम : ANANTCORP. बम्बई 11.

बिक्री और सेवा : दिल्ली • मद्रास • बंगलौर • कोयम्बतूर • हैदराबाद • पूणे • वडोदरा • मदुरै • गोवा • वापी • चंडीगढ़

ATCO
सही माप मिले हर बार मिले.

maadhyam

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रविशंकर, इंडियन एक्सप्रेस

- विपक्षी दलों की एकता एक मृगतृष्णा के समान है. ■ **रामकृष्ण हेगड़े,** *आज*

- मैं तो इन वामपंथियों को बेपेंदी का मानता हूं. ■ **लालकृष्ण आडवाणी,** *धर्मयुग*

- मैं संत की मुद्रा में नहीं हूं, संघर्ष की मुद्रा में जरूर हूं.
■ **विश्वनाथ प्रताप सिंह,** *स्वतंत्र भारत*

- वी.पी. सिंह तो किसी तरह जेल जाने का उपाय सोच रहे हैं.
■ **गुलाम नबी आजाद,** *माया*

- जो लोग सच बोलते हैं उन्हें असंतुष्ट नहीं कहा जा सकता.
■ **शिवचरण माथुर,** *राजस्थान पत्रिका*

- वे (असंतुष्ट) तो चाहते हैं कि मैं कोई कड़ा बयान दे दूं और उन्हें इसका राजनैतिक फायदा मिल जाए. लेकिन अब मैं भी थोड़ी राजनीति सीख गया हूं.
■ **शंकर राव चव्हाण,** *इलस्ट्रेटेड वीकली*

- (बिहार के) दुबे मंत्रिमंडल में कोई ऐसा भी है जो भ्रष्ट नहीं है?
■ **जगन्नाथ मिश्र,** *दिनमान*

- आप निश्चिंत रहिए. मैंने ऐसा इंतजाम कर दिया है कि दुनिया से मेरे विदा होने के वर्षों बाद तक इंडियन एक्सप्रेस का झंडा ऊंचा लहराता रहेगा.
■ **रामनाथ गोयनका,** *जेंटलमैन*

- मुझे एक भी ऐसा क्रिकेट कप्तान दिखा दीजिए जो यह कहे कि उसे कप्तानी करने में मजा आया, तो मैं साबित कर दूंगा कि वह ईमानदारी से वैसा नहीं कह रहा है.
■ **कपिलदेव,** *स्पोर्ट्सवीक*

- यह कुश्ती का दुर्भाग्य नहीं है तो और क्या है कि ओलंपिक में पी.टी. उषा चौथा स्थान ले आए तो उसे लोग और सरकार सिर उठा लेती है. वहीं (कुश्ती में) राजिंदर चौथा स्थान पाता है तो लोगों को उसकी ओर देखने की फुरसत भी नहीं मिलती.
■ **मास्टर चंदगी राम,** *जनसत्ता*

- जहां तक ग्लेमर का सवाल है तो वह तो मेरे चेहरे पर अंकित है.
■ **किमी काटकर,** *दैनिक जागरण*

- सब मुकद्दर पर निर्भर करता है. अगर मुझे नंबर वन होना है तो काले दांत के बावजूद हो जाऊंगी.
■ **डिंपल कपाड़िया,** *रविवार*

भरिए

यह कूपन और अपनी चहेती आवाज़ सुनिए: बच्चे की खिलखिलाहट

हंसी-खुशी और मौज-मस्ती बच्चों के लिए उतनी ही ज़रुरी हैं जितने ज़रुरी हैं खाना-पीना और हवा. और डिस्नी टुडे लेकर आया है यही मस्ती... यही मज़े.
बस तो फिर यह कूपन भर दीजिए और हर एक को खुश कर दीजिए.

आकर्षक छूट का लाभ उठाईये.

कूपन निम्नलिखित पते पर भेजें:
लिविंग मीडिया इंडिया (प्रा.) लि.
सबस्क्रिपशन डिपार्टमेंट
थॉमसन प्रेस बिल्डिंग
पो.बॉ. न० 69, दिल्ली-मथुरा रोड
फ़रीदाबाद - 121 007 (फ़रीदाबाद)

मुझे अपने बच्चे के लिए सबस्क्रिपशन चाहिए. यह रहा मेरा ☐ सालाना: रु. 78/- ☐ छह महीने का: रु. 40/- हिन्दी प्रति के लिए सबस्क्रिपशन मैं भुगतान चैक/मनी आर्डर/डिमांड ड्राफ्ट न. _____ द्वारा कर रहा हूं. कृपया प्रति निम्नलिखित नाम व पते पर भेजें:

नाम _____
उम्र _____ लिंग _____
डाक-पता _____
_____
_____
विद्यालय _____
माता-पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर _____

कृपया भुगतान लिविंग मीडिया इंडिया (प्रा.) लि. के नाम पर बनाएं

Wicomics डिस्नी टुडे

अब उपलब्ध हर पखवाड़े हिन्दी और अंग्रेज़ी में

© 1987 THE WALT DISNEY CO., USA.

MILESTONES/DT/114 Hin a

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जानकार लोगों की चाहत
ऐस्प्रो राहत

सरदर्द का
बेहतरीन
उपचार

दुनिया भर के करोड़ों लोगों की विश्वसनीय दवा

daCunha/AS/41/87 HIN

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नया राष्ट्रीय शगल

■ जब से देश में वीडियो का प्रचलन शुरू हुआ है तब से घर बैठे बिठाए फिल्में देखने के शौक ने मुख्य राष्ट्रीय शगल का रुतबा प्राप्त कर लिया है. और अब तो हालत यह हो चुकी है कि छोटे-

सभी कार्टून अनिल शर्मा

छोटे कस्बों और गांवों में वीडियो पार्लर खुल जाने से उन लोगों तक भी वीडियो की पहुंच हो गई है जो अपना वीडियो-टीवी खरीदने की हैसियत नहीं रखते. नतीजा यह हो रहा है कि गैरकानूनी तौर पर वीडियो पार्लर चलाने वाले लोग खूब पैसा कमा रहे हैं. पिछले पखवाड़े जयपुर के निकट एक कस्बे में स्थानीय वाणिज्य कर अधिकारी ने छापा मारकर ऐसे पांच अवैध पार्लरों का पता लगाया. लेकिन इस छापे में उन्हें जो कुछ देखने को मिला वह उनकी कल्पना से भी बाहर की चीज थी.

एक पार्लर में जब छापा मारा गया तो पाया गया कि लगभग 400 बच्चे अपने स्कूल से भागकर वहां हिंदी फिल्म देख रहे थे. छापा पड़ता देख बच्चे ऐसे घबराए कि अपने पीछे अपने जूते और बस्ते भी छोड़ गए. बस्तों की जांच करने पर पता चला कि कई किलोमीटर दूर के स्कूलों के बच्चे भी वहां फिल्म देखने आए हुए थे.

इसी तरह एक पार्लर वाले ने छापे की खबर सुनते ही अपने शटर गिरा दिए. लगभग एक घंटे तक तो डरे हुए बच्चे अंदर चुप बैठे रहे पर शटर न खुलने पर जब उन्होंने सामूहिक रूप से रोना शुरू किया तो अधिकारियों ने पार्लर के शटर का ताला तोड़ा और तब कहीं बच्चों को बाहर निकाला गया.

कुत्तों के रंग न्यारे

■ खूबसूरती ढूंढने के लिए आए दिन महिलाओं की सौंदर्य प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं जिनमें 'मिस कॉलेज' से लेकर 'मिस यूनिवर्स' तक का चुनाव किया जाता है. इसी तरह पुरुषों के लिए 'बॉडी बिल्डिंग' प्रतियोगिताएं होती हैं. लेकिन पिछले दिनों बंबई के कुत्ताप्रेमियों ने जिस प्रतियोगिता का आयोजन किया वह अपनी तरह की अनूठी रही.

भारतीय राष्ट्रीय कुत्ता प्रेमी क्लब ने इस बार अपनी सालाना कुत्ता प्रदर्शनी के अंत में कुत्तों के फैंसी ड्रेस के शो का आयोजन किया जिसमें तरह-तरह की वेशभूषा में सजे हुए कुत्तों और उनके मालिकों ने हिस्सा लिया. आकर्षण का सबसे प्रमुख केंद्र पूडल नस्ल का एक कुत्ता रहा जिसे लहंगा-चोली और मुकुट पहनाकर दुलहन की तरह सजाया गया था. दुलहन की तरह ठुमकने वाले इस पूडल के बाद दूसरा स्थान एक पग कुत्ते का रहा जो अपनी चपटी नाक के बावजूद गुजराती दुलहन के जोड़े में काफी सुंदर लग रहा था. इस शृंखला में तीसरा स्थान एक डाबर-मैन-पिंचर नस्ल के कुत्ते का रहा जिसे उसके मालिक ने पीले रंग की धोती पहनाकर और वीणा देकर 'नारद' बनाया था. हालांकि इस प्रतियोगिता को देखने के लिए बंबई और आसपास के इलाकों से

लगभग 1500 लोग आए पर इसके बावजूद आयोजकों को यह शिकायत रही कि टिकटों की बिक्री से उनका खर्च नहीं निकल पाया. लेकिन कुत्तों और उनके मालिकों के लिए यह अनुभव अनूठा रहा.

पिए कोई, भरे कोई

■ हिंदुस्तानी पुलिस की महिमा अपरंपार है. शिकायत करने के बावजूद रिपोर्ट न लिखना; रिपोर्ट लिखने के बाद भी कार्रवाई न करना और कार्रवाई करने के बावजूद अपराधियों को खुला

छोड़ देना ऐसी शिकायतें हैं जिन्हें अब एक स्थायी सच मान लिया गया है. लेकिन पिछले पखवाड़े लखनऊ पुलिस ने जो कमाल कर दिखाया है वह इस परंपरा से भी कहीं अधिक जोरदार रहा.

एक समाचार के अनुसार स्थानीय कृष्णनगर थाना के एक सब-इंस्पेक्टर ने दो साल पहले शराब पीने के अपराध में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया. अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज करके उसे हवालात में डाल दिया गया. अगले दिन अभियुक्त के भाई ने दो हजार रुपए की जमानत देकर उसे छुड़ा लिया. लेकिन बाद में जब इस मामले में आरोप पत्र तैयार किया गया तब अभियुक्त के स्थान पर उसकी जमानत देने वाले भाई का नाम लिख दिया गया. मामला जब अदालत में पेश किया गया तब कटघरे में भी भाई को खड़ा कर दिया गया. हालांकि असली अभियुक्त ने अदालत के सामने मामला साफ करने की कोशिश की लेकिन उसे इस आधार पर दखल देने से रोक दिया गया कि उसका इस मामले से कोई संबंध नहीं. मामला दो साल तक लटका रहा और पिछले पखवाड़े तब हल हुआ जब अभियुक्तों के वकील ने न्यायाधीश के सामने तथ्य पेश किए. मुकदमा खारिज हुआ और असली अभियुक्त भी आराम से छूट गया.

बंदरों की मौज

■ बंबई जैसे शहर में दादाओं, स्मगलरों और उचक्कों की जो अनूठी भरमार है उसके कारण स्थानीय पुलिस और प्रशासन का व्यस्त रहना स्वाभाविक ही है. शायद यही कारण था कि कोलाबा के एक इलाके में बंदरों से परेशान नागरिकों की शिकायतों को स्थानीय थाने और महानगर पालिका के अधिकारी एक लंबे अरसे से अनसुना करते चले आ रहे थे. इस सरकारी उदासीनता के चलते बंदरों की ऐसी मौज बनी हुई थी कि वे जब चाहें किसी भी राहगीर को काट खाएं और उसके हाथों से खाने-पीने का सामान छीन कर उसका आनंद लूटें.

लेकिन पिछले दिनों अचानक ही प्रशासन की आंख खुली और पुलिस ने नागरिकों को इस मुसीबत से छुटकारा दिलाने का फैसला कर लिया. आनन-फानन में रणनीति बनी और देखते-ही-देखते उत्पाती बंदरों को 'गिरफ्तार' कर लिया गया. पर अब समस्या यह आई कि इन 'अपराधियों' को किस हवालात में बंद किया जाए. आखिर एक अधिकारी को इस समस्या का हल मिल गया और बंदरों को अगली कार्रवाई होने तक स्थानीय थाने के उस कमरे में बंद कर दिया गया जहां फेरीवालों और खोमचेवालों से पकड़ा गया खाने-पीने का सामान बंद किया

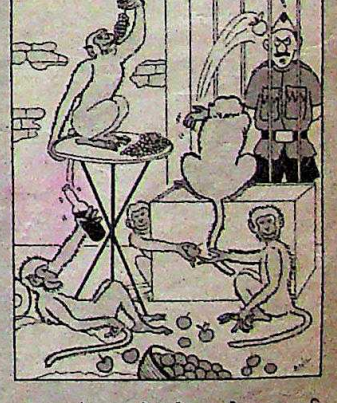

जाता है. बंदरों को मानो मनचाही मुराद मिल गई. खाने-पीने के सामान पर उन्होंने जमकर हाथ साफ किए और उछल-कूद कर लोगों का मनोरंजन भी किया.

—संकलन: विजय क्रान्ति

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हिन्दी की प्रथम प्रामाणिक वार्षिकी

नवीनतम आँकड़ों पर आधारित

उत्कृष्ट, प्रामाणिक, सारगर्भित

सन्दर्भ ग्रन्थ

आधुनिक विषयों का सुन्दर आंकलन

सरल एवं सुस्पष्ट शैली में

विश्वसनीय अनुपम भेंट

मूल्य ६०/-

विविध विषयक, सार्वभौमिक विपुल सामग्री का समावेश

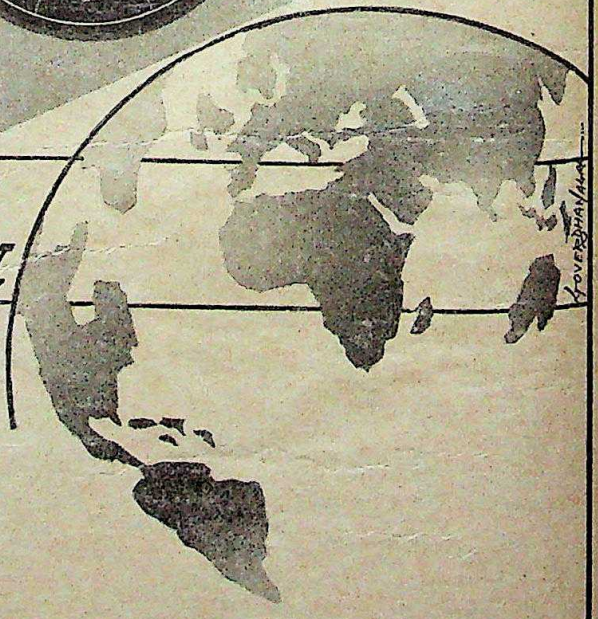

- आधुनिक भारतीय इतिहास एवं संस्कृति
- भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन
- भारतीय राजनीति एवं संविधान
- भारतीय भूगोल एवं अर्थव्यवस्था
- योजनागत विकास
- भारत में प्राविधिक एवं वैज्ञानिक विकास
- आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक समन्वित विकास
- खेलकूद
- पुरस्कार एवं अलंकार
- विभिन्न क्षेत्रों में विश्व के पाँच शीर्षस्थ देश
- गुट निरपेक्षता
- भारत एवं विश्व के विविध क्षेत्रों के महत्वपूर्ण आँकड़े एवं मुख्य सूचनाएँ

YOUR SUCCESS IS OUR AIM SURE SUCCESS WITH OUR NAME THAT IS UPKAR

उपकार प्रकाशन
2/11 ए, स्वदेशी बीमा नगर, आगरा -282 002

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भविष्य का आईना

सत्ता के सम्मोहन से बिंधा रहा बीता पखवाड़ा. और ढिंढोरची या तो अतीत के गौरव की गाथा गाते रहे या भाग्यशाली भविष्य की भविष्यवाणी करते रहे. आजादी के 41वें वर्ष में देश की कुव्यवस्था के इतने सटीक प्रतीक कभी नहीं बने थे गणतंत्र समारोह के गरिमापूर्ण आयोजन.

राजपथ पर भारतीय सेना की भड़कीली भंगिमा श्रीलंका में उनकी मौजूदगी की भी हल्की याद दिला रही थी. और उसे निहारने वालों में मुख्य अतिथि के रूप में बैठी थी वह हस्ती जो उसकी मौजूदगी से मुक्ति पाने के महती दबाव से आज गुजर रही है. लेकिन इस भंगिमा का बांकापन बोफोर्स तोप में ही झलका जो आज भी घोटालों के घटाटोप आरोपों से घिरी है. राजपथ पर पंजाब पुलिस के कदम भले ही शान से एक लय में आगे बढ़ते दिखे लेकिन अपने राज्य में लड़खड़ाए ही नजर आए.

हामिद अली

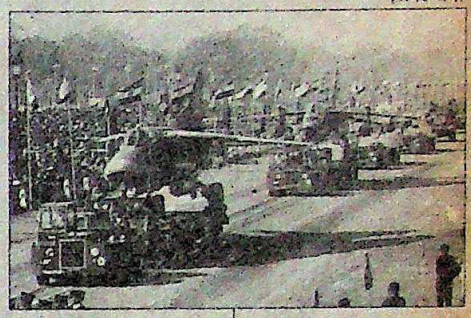

गणतंत्र दिवस की शोभायात्राओं ने देश की कुव्यवस्था को जैसे कुछ देर के लिए छिपा दिया

प्रशांत पंजियार

राजस्थान में मुख्यमंत्री का फेरबदल दरबारी उखाड़-पछाड़ का ही एक नमूना रहा

चारों ओर जो अफरातफरी दिखी उसमें राष्ट्रप्रेम का यह अचानक प्रदर्शन कुछ अटपटा ही लगा. राजस्थान में मुख्यमंत्री का परिवर्तन दरबारी उखाड़-पछाड़ से ज्यादा पार्टी के अंदर लोकतंत्र का तिरस्कार ही जाहिर कर गया. हरिदेव जोशी की जगह जिसे कुर्सी पर बिठाया गया उसे पार्टी विधायकों के बहुमत का समर्थन हासिल नहीं था. इससे भी ज्यादा अहम बात यह कि राजनैतिक रूप से अपेक्षाकृत स्थिर राज्य को अस्थिरता की राह पर धकेल दिया गया. सत्ता का इतना केंद्रीकरण पहले कभी देखने में नहीं आया था.

पीआइबी

राजीव गांधी की स्वीडन यात्रा के दौरान बोफोर्स का प्रेत जैसे सोया रहा

पंजाब के बारे में सरकार की आशावादिता 'ऑपरेशन ब्लूस्टार' के बाद के शायद सबसे खूनी पखवाड़े की हकीकतों से टकराकर चूर-चूर हो गई. लेकिन राय और रिबेरो पर अत्यधिक निर्भरता के कारण कुछ कर सकने की गुंजाइश भी जैसे सीमित हो गई है. उधर पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड आंदोलन हिंसक होता जा रहा है और सिक्किम जैसे राज्यों को भी अपनी चपेट में लेने की ओर प्रवृत हो रहा है, जबकि केंद्र नरमी की नीति पर ही कायम रहा है. दूर दक्षिण के तमिलनाडु में दो भद्र महिलाओं का सत्ता संघर्ष जारी रहा, हालांकि दोनों ही इस नाजुक राज्य को संभालने की कुव्वत नहीं रखतीं.

पीआइबी

सरहदी गांधी उन महामानवों की पीढ़ी के अंतिम व्यक्ति थे जो कभी इस उपमहाद्वीप की शोभा रहे

श्रीलंका की हालत यह रही कि जयवर्धने खुद अलग-थलग पड़ते, और भारत के साथ विशेष संधि पर जोर देते दिखे. यानी भारत पर न केवल तमिल चीतों पर काबू करने का उत्तर-दायित्व होगा, बल्कि एक बिखरती सत्ता को संभालने का भी.

एक प्रेतबाधा शायद मिट गई. प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा में निरस्त्रीकरण पर ही चर्चा हुई. 'शस्त्रीकरण' के जिस प्रेत से भारत में हड़कंप मचा था उसकी छाया तक स्वीडन से आई खबरों में नहीं दिखी. लेकिन देश विभाजन का भूत शायद कभी शांत नहीं होगा. टीवी सीरियल 'तमस' के प्रसारण पर रोक लगवाने की कोशिशें न्यायिक फैसले के कारण भले ही कुछ समय के लिए नाकाम हो गई हों, लेकिन सांप्रदायिक दलों का कट्टरवाद अपने नंगे रूप में उभर कर सामने आ गया. और इस प्रक्रिया में उन्होंने 'तमस' के इस कथ्य को ही जैसे सिद्ध कर दिया—इतिहास की उपेक्षा करने वाले उसे फिर से दोहराने को अभिशप्त होते हैं.

और इस तथ्य को जिस विभूति ने शायद सबसे अच्छी तरह समझा था वह इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा हो गई. आजादी की लड़ाई के अगुआ में शुमार सरहदी गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां का पेशावर में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया. जलालाबाद की जमीन के नीचे उनके साथ ही जैसे वे आदर्श दफन हो गए जिन्होंने महामानवों की उस पीढ़ी को रूपाकार दिया था जो कभी इस महाद्वीप की शोभा थे. —दिलीप बॉब

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

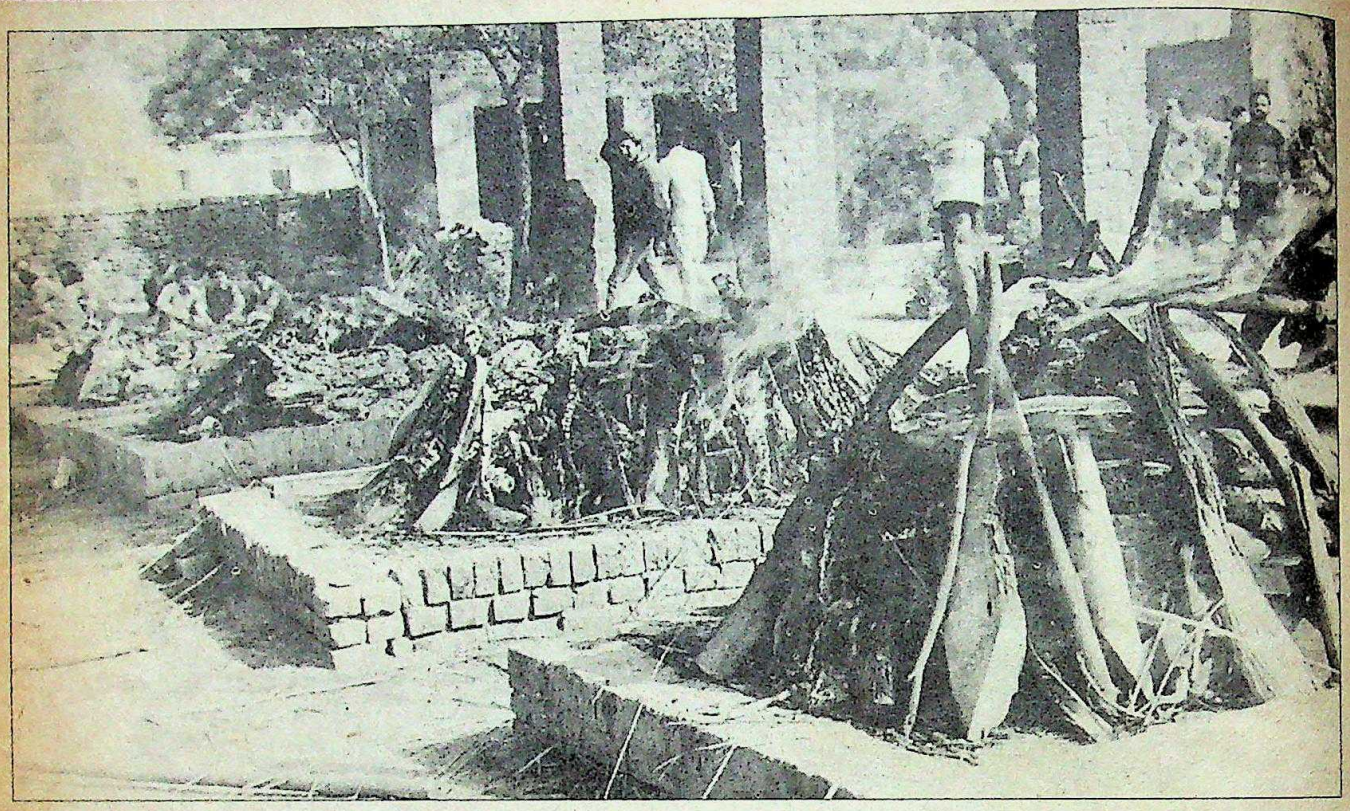

बरनाला हत्याकांड में मरे लोगों की सामूहिक अंत्येष्टिः हृदयद्रावक

पंजाब

अंधियारा फिर घिर आया

आतंकवादी सुरक्षा बलों से एक कदम आगे रहने की तैयारी में

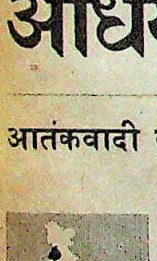

पंजाब में नया साल भय और संत्रास लेकर आया. आतंकवादियों ने 1988 के पहले चार दिनों में ही 44 लोगों की नृशंस हत्या करके पिछले कुछ महीनों में आई मामूली शांति छिन्न-विच्छिन्न कर दी. इन हत्याओं ने राज्यपाल सिद्धार्थशंकर राय के इस दावे को एकदम झुठला दिया कि राज्य में स्थिरता फिर लौट रही है.

लगता है कि आतंकवादियों ने नए साल में फैसला कर लिया है कि वे सुरक्षाबलों से एक हाथ आगे ही रहेंगे. साल के पहले ही दिन की हत्याओं से उन्होंने इसे अमली जामा पहनाना प्रारंभ कर दिया. परिवार के परिवार खत्म करने वाली सामूहिक हत्याएं पूरे महीने होती रहीं. जिंदगी जैसे लाशों की गिनती का खेल बन गई. हाल यह था कि 25 जनवरी तक मृतकों की संख्या 129 तक पहुंच गई.

आतंकवाद की अचानक शुरू हुई इस लहर ने पूरे पंजाब के उन लोगों को पंगु कर दिया जो आतंकवाद से मुकाबला कर रहे थे. इस बार हत्याएं खासकर अशांत कहे जाने वाले अमृतसर, गुरदासपुर और फिरोजपुर जिलों में नहीं हुई बल्कि अपेक्षाकृत शांत माने गए संगरूर, फरीदकोट और होशियारपुर जिलों में हुईं. पंजाब पुलिस के प्रमुख जे. एफ. रिबेरो ने कहा, "आश्चर्य की बात है कि हाल में हुई इन हत्याओं में कोई एक निश्चित तरीका अख्तियार नही किया गया. वे पूरे राज्य में आतंक फैला देना चाहते थे, जिससे हम किसी एक स्थान पर अपना ध्यान केंद्रित न कर सकें" (देखें बातचीत). लोगों में घर कर रही इस धारणा पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि शक्तिशाली आतंकवादी किसी भी स्थान पर और किसी भी समय हमला कर सकते हैं. यह धारणा उतनी ही खतरनाक है जितनी हिंसक वारदातों में बढ़ोतरी.

खूफिया सूत्रों का मानना है कि पिछले महीने पाकिस्तान में हुई एक बैठक में अमेरिका, कनाडा और भारत के खालिस्तान समर्थकों ने पंजाब में संघर्ष की नई रणनीति तैयार की

लगता है कि आतंकवादियों ने 1987 के अंतिम महीनों में अपनी रणनीति को फिर से बदला है. खूरेजी पर उतारू आतंकवादियों का निशाना अब वे लोग नहीं हैं जो पहले प्रतीत हो रहे थे. अब वे एकबारगी कई मोर्चों पर वार कर रहे हैं. जिस पर भी पुलिस का भेदिया होने का उन्हें थोड़ा भी संदेह होता है उसे वे बस खत्म करके ही दम लेते हैं. और मौका लगने पर चुनिंदा पुलिस अधिकारियों की हत्या और अर्धसैनिक बलों पर हमला करने से भी वे बाज नहीं आते.

ज्यादातर हत्याएं नृशंस तरीके से की जाती हैं. मसलन 15 और 23 जनवरी के बीच फरीदकोट, गुरदासपुर और अमृतसर जिलों में तीन परिवारों को समाप्त कर दिया गया. इन परिवारों के मारे गए 20 सदस्यों में से 11 महिलाएं और बच्चे थे. गुरदासपुर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

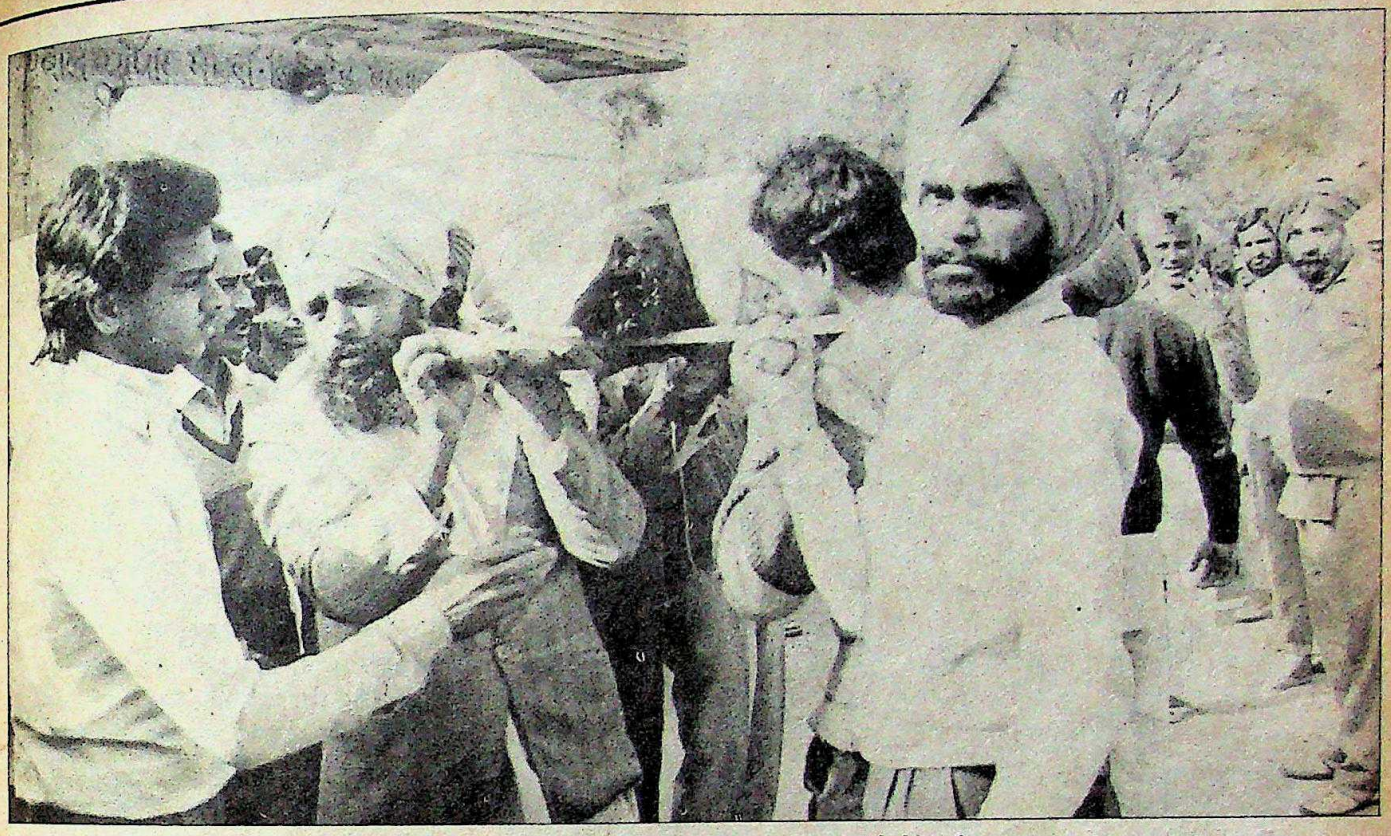

चार्ट: बी.के. शर्मा

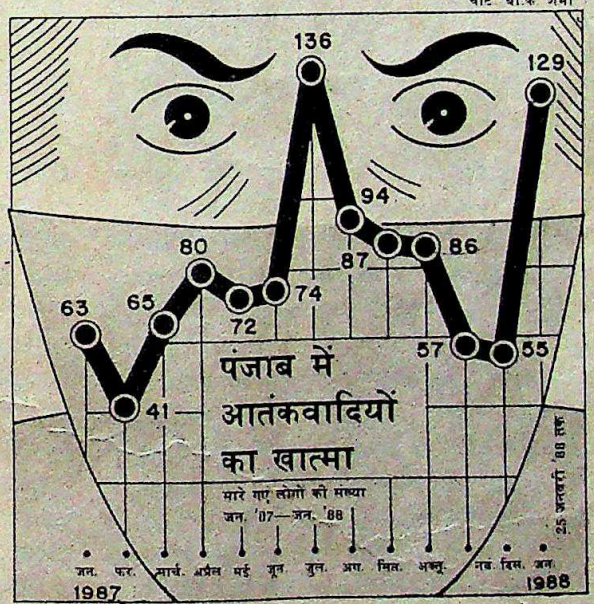

शोक संतप्त हिंदू और सिख: मिल कर दुख बांट लें

के कोटली फास्सी गांव में मारे गए एक परिवार के पांच सदस्यों को छोड़कर बाकी सभी मृतक सिख ही थे.

पिछले महीने आतंकवाद के शिकार होने वालों में विभिन्न दलों के नेता शामिल थे. इनमें इंका के दो नेता त्रिलोचन सिंह रियासती और पूर्व मंत्री जगतराम प्रमुख हैं. रियासती सरकार और आतंकवादियों को बातचीत की मेज पर लाने का प्रयास कर रहे थे. पंजाब भाजपा के उपाध्यक्ष खुशीराम शर्मा ने कई अवसरों पर आतंकवाद की निंदा की थी. उनकी भी हत्या कर दी गई. हत्या के कुछ असफल प्रयासों में से एक है वरिष्ठ अकाली नेता और शिरोमणि गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष काबुल सिंह पर हुआ घातक हमला.

सबसे बर्बर सामूहिक हत्याकांड संगरूर जिले के बरनाला गांव में हुआ. 22 जनवरी की सुबह बाबा आला सिंह म्युनिसिपल पार्क में चहलकदमी कर रहे अल्पसंख्यक समुदाय के 10 व्यक्तियों को भून दिया गया.

अगले ही दिन भाजपा और दूसरे हिंदू संगठनों ने पंजाब बंद का आह्वान किया जो संगरूर में पूरी तरह सफल और बाकी क्षेत्रों में आंशिक सफल रहा. परंतु यह आतंकवादियों को भटिंडा के एक बैंक से 1.1 लाख रुपए लूटने से नहीं रोक पाया. पिछले महीने उग्रवादियों द्वारा डाली गई यह तीसरी बैंक डकैती थी. 15 जनवरी को हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के एक राष्ट्रीयकृत बैंक से 1.3 लाख रुपए लूट लिए गए.

पंजाब के सुरक्षा बलों के उच्च अधिकारियों का मानना है कि हिंसा की ताजा घटनाएं आतंकवादियों की रणनीति में भारी बदलाव का परिणाम हैं. वे मानते हैं कि नई रणनीति पिछले वर्ष किसी समय पाकिस्तान में बनी. इसे तैयार किया अमेरिका और कनाडा के कुछ खालिस्तान समर्थकों ने, पंजाब के कुछ आतंकवादी गुटों के सदस्यों के साथ मिलकर. उन बैठकों में कथित खालिस्तान परिषद का स्वयंभू प्रमुख गुरनाम सिंह औलख मौजूद था. इस परिषद के अधिकांश सदस्य अमेरिका में बसे सिख हैं.

विश्वस्त खुफिया सूचनाओं के अनुसार पाकिस्तान में उस समय जो प्रमुख आतंकवादी मौजूद थे उनमें बब्बर खालसा का सुखदेव सिंह और वाधवा सिंह, दमदमी टकसाल का गुरनाम सिंह वडसाला और वासन सिंह जाफरवाला शामिल हैं. खुफिया सूत्रों का विश्वास है कि कुछ बैठकों में तो पाकिस्तान के खुफिया संगठन 'इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसी' के लोग भी सलाह-मशविरे के लिए शरीक थे.

सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान में हुई बैठक में जो नई योजना बनाई गई उसमें और बातों के अलावा हिंसक वारदातें बढ़ाना, आतंक फैलाने के नए तरीके आजमाना और छिपने के ठिकाने बदलते रहना शामिल है. एक महत्वपूर्ण नतीजा यह भी रहा कि पंजाब में कार्यरत आतंकवादी गुटों को और अधिक हथियार और धन देने का वायदा किया गया. इस तरह उनमें एक नया विश्वास पैदा करने की कोशिश की गई. परंतु एक गुत्थी रह जाती है. पिछले साल के आखिरी दिनों में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जूलियो फ्रांसिस रिबेरो

'वे हमारा ध्यान बंटाना चाहते हैं'

पंजाब में फिर से अंधाधुंध हत्याओं का सिलसिला जारी हो गया है. इस हालत में पुलिस क्या कदम उठाना चाहती है, इसकी पड़ताल के लिए वरिष्ठ संवाददाता ***विपुल मुद्गल*** *की पंजाब पुलिस के प्रमुख जूलियो फ्रांसिस रिबेरो से बातचीत के अंश :*

● ***पिछले कुछ महीनों में पंजाब के आतंकवादियों पर पुलिस हावी रही है. क्या अब यह स्थिति बदल गई है?***

कभी हम उन पर हावी रहते हैं, कभी हमारी पकड़ थोड़ी कमजोर हो जाती है. मेरे कार्यकाल के 21 महीनों में दूसरी दफा आतंकवादियों की गतिविधियों में तेजी आई है. वे 1986 में लंबे समय तक पुलिस के दबाव में थे. लेकिन आप जल्दी ही उन्हें बचाव की मुद्रा में पाएंगे.

● ***क्या आपको हत्याओं के पीछे कोई साजिश दिखाई देती है?***

उनकी कोशिश है कि हम सीमा से सटे अशांत जिलों पर खुद को केंद्रित न कर सकें. वे जगत्तराम, खुशीराम शर्मा और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के नेता काबुल सिंह जैसे कमजोर सुरक्षाबाले लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं जिससे कम जोखिम उठाकर ज्यादा आतंक फैलाया जा सके.

● ***आप इस हिंसा पर कैसे काबू पाएंगे?***

इस स्थिति से निबटने के लिए हमने एक विस्तृत योजना बनाई है. आप जल्दी ही इसका असर देख सकेंगे. फिलहाल मैं योजना पर ज्यादा प्रकाश नहीं डाल सकता.

● ***ग्रामीण इलाकों में सुरक्षा बलों की विश्वसनीयता इतनी संदेहास्पद क्यों बनी हुई है?***

हमारे देश में किसी की विश्वसनीयता संदेह से परे है? राजनैतिक नेताओं, न्यायपालिका या अखबारी दुनिया की? मैं अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने की कोशिश करता हूं.

● ***लेकिन पुलिस मुठभेड़ों की बड़ी बदनामी हुई है. क्या ऐसी कार्रवाइयों से लोगों का विश्वास नहीं उठ जाता?***

झड़पों में वे हमारे आदमियों को मारते हैं और हम उनके. जब हमारे आदमी मारे जाते हैं तब कोई कुछ नहीं कहता. लेकिन हमारे आदमी जब उनके कुछ लोगों को मारने का मौका पा जाते हैं तो चारों तरफ शोर मच जाता है.

● ***क्या आपको नहीं लगता कि हत्याओं का उलटा असर भी होता है?***

असल में, जरूरत लोगों के दिल जीतने की है. इसी मोर्चे पर हम नाकाम रहे हैं. लेकिन सिख समुदाय पुलिस का

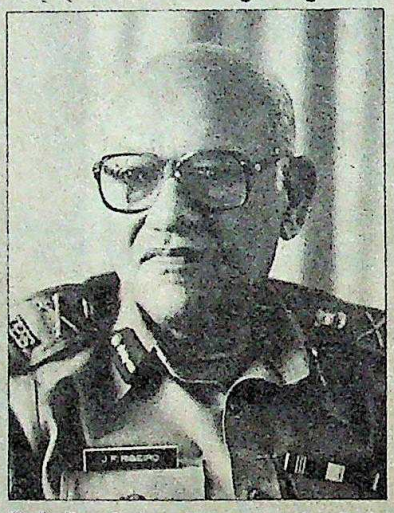

विरोधी नहीं है. मुझे पक्का यकीन है कि सिखों को दबाया नहीं जा सकता. मैं अपने आदमियों से कहता हूं कि किसी के आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचाओ. परेशान किए जाने के मामले सामने आने पर मैं तुरंत कार्रवाई करता हूं.

● ***लेकिन असरदार कानून बनाने के बाद भी आतंकवाद के मामले आप अदालतों को क्यों नहीं सौंपते?***

अब हम किसी एक्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट से पुलिस हिरासत नहीं मांग सकते. सिर्फ अमृतसर जिले में ही 700 संदेहास्पद आतंकवादी और उनके सरपरस्त जमानत पा गए हैं. इन्हीं युवकों में से कई हाल में हुई हत्याओं में शामिल थे.

● ***लेकिन नए साक्ष्य अधिनियम के कारण अब हिरासत में की गई स्वीकारोक्ति भी अदालत में मान्य हो गई है.***

इस कानून में कोई बड़ी तबदीली नहीं हुई है. कबूल करने का मतलब स्वीकारोक्ति नहीं होता. वैसे मैं भविष्य में इसका निश्चित ही उपयोग करूंगा.

बढ़ी हिंसक वारदातों में करीब-करीब सभी कुख्यात आतंकवादियों की भूमिका न के बराबर ही रही है.

और अपने सबसे सुरक्षित ठिकाने स्वर्ण मंदिर तक उनकी लगातार पहुंच ने पिछले महीनों में आतंकवादियों का काम निश्चित ही काफी आसान किया. सीआरपी की टुकड़ियों के मंदिर के प्रवेश द्वार से हटा लिए जाने से कम-से-कम 60 से 80 आतंकवादी अंदर पहुंच गए. रिबेरो का कहना है, "नरसंहार और अन्य अपराधों की अधिकांश योजनाएं अभी भी वहीं बनाई जाती हैं." इसी तरह मंदिर में आने वाले नागरिकों से पैसा ऐंठना भी निरंतर जारी है. रिबेरो के अनुसार टुकड़ियां पूरी तरह नहीं हटाई गई हैं.

पिछले महीने आतंकवादियों ने जिस आसानी से बार-बार कहर ढाए उससे तो कतई नहीं लगता कि उनके 'पैर उखड़ गए हैं' जैसा कि राय बार-बार दावा करते रहे हैं. पिछले वर्ष नवंबर-दिसंबर में कुछ समय तक तो सुरक्षा बल हावी थे, लेकिन अब फिर से आतंकवादी हावी हो गए हैं. उन्होंने दहशत फैला दी है यही उनकी जीत नहीं है. राजनैतिक अर्थों में भी वे बीस ही साबित हुए हैं. अकाली नेता और पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की उलझनपूर्ण उदारपंथी नीति को आम मान्यता नहीं मिली तो इसका श्रेय भी पूरी तरह आतंकवादियों को ही जाता है. पिछले महीने जब बादल का जनसंपर्क कार्यक्रम चल रहा था, तो सामूहिक हत्याओं का दौर भी जारी था. इस कारण उनके कार्यक्रम बेअसर ही रहे.

रिबेरो अपने मित्रों और करीबी लोगों से जो कुछ कहते रहे हैं उससे प्रशासन की असहायता ही झलकती है. उनका मानना है कि सुरक्षा बल उतना ही कर सकते हैं जितना अब तक करते रहे हैं. मतलब यह है कि राजनैतिक समाधान नहीं हुआ तो हत्याएं जारी रहेंगी.

आतंकवादी जैसे-जैसे एकजुट और मजबूत होते जा रहे हैं और विदेशी आकाओं से उनकी रफ्त-जफ्त जैसे-जैसे बढ़ती जा रही है, विवेकसम्मत राजनैतिक स्वर अवरुद्ध होते जा रहे हैं. एक ओर इंका की मुसीबत यह है कि वह राज्य में राष्ट्रपति शासन जारी रहने के औचित्य की वकालत करने में परेशानी महसूस कर रही है. दूसरी ओर अकाली नेता हैं जो उन्हीं सभामंचों से शासन की घोर निंदा करते हैं जिन पर उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस का भारी बंदोबस्त होता है. और कितने बेचारे-से दिखते हैं वे!

—विपुल मुद्गल

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'तमस'

सांच पर आंच

कट्टरपंथियों के नए तेवर

तीन दिनों तक यही अंदेशा बना रहा कि बंटवारे पर आधारित गोविंद निहलाणी के छह भागों वाले बहुचर्चित सीरियल 'तमस' का प्रदर्शन बीच में ही रोक लिया जाएगा. 21 जनवरी को बंबई हाई-कोर्ट ने स्थानीय उद्योगपति जावेद सिद्दीकी की याचिका पर इस सीरियल के आगे प्रसारण पर रोक लगा दी थी. याचिका में कहा गया था कि यह सीरियल 'लोगों के जेहन में फिरकापरस्ती का जहर घोल देगा.'

बाद में 23 जनवरी को न्यायमूर्ति बख्तावर लेंटिन और सुजाता मनोहर ने यह अस्थायी आदेश रद्द करके 'तमस' के तीसरे प्रकरण के प्रसारण की अनुमति दे दी. शिवसेना और जनता युवा मोर्चे ने इस फैसले का विरोध किया.

न्यायाधीशों ने सीरियल के पक्ष में निर्णय देते हुए कहा कि "यह हिंदु-मुसलमान दोनों ही समुदायों के कट्टरपंथियों पर हमला करता है. इसका असली निशाना सांप्रदायिकता है और इसमें उग्रवाद की सच्ची तस्वीर है. जब दोनों तबकों को असलियत पता चलती है, तो वे एक हो जाते हैं."

'तमस' के खिलाफ यह हो-हल्ला उन तबकों की दिनोदिन बढ़ती संकीर्णता का ताजा नमूना है जो अपनी आस्थाओं की रक्षा के लिए आगे आए हैं.

मसलन 1982 में शिवसेना ने पुणे की थिएटर अकादमी को बर्लिन जाने से रोकने की कोशिश की थी. उसके मुताबिक विजय तेंदुलकर द्वारा लिखित और जब्बार पटेल द्वारा निर्देशित नाटक 'घासीराम कोतवाल' में नाना फडनवीस और मराठा साम्राज्य की अवमानना की गई थी. हालांकि बाद में नाटक खेला गया पर तभी जब अकादमी ने विदेशों में दिखाए जाने वाले नाटक का पाठ इस रूप में बदल लिया जिससे कि शिवसेना संतुष्ट हो सके.

नाटकों के हिंसक विरोध की कई मिसालें हैं. पिछले साल जनवरी में विक्रम सावरकर की अगुआई वाली हिंदू महासभा और आर्य प्रतिनिधि सभा ने पृथ्वी थिएटर में खेले जा रहे हिंदी नाटक 'शेक्सपियर की रामलीला' को बंद करा दिया था. यह एक हास्य नाटिका थी जिसमें रोमियो और जूलियट को रामलीला में दिखाया गया था. इसे हिंदू धर्म पर एक कलंक बताते हुए विरोध करने वालों ने पात्रों को गालियां दीं और नाटक के लेखक इकबाल ख्वाजा को खुलेआम अपमानित भी किया.

पी.एम. एंथनी के मलयाली नाटक 'क्रिस्तुविंदे आराम थिमुरिवु' (ईसा का छठा पवित्र घाव) का भी ऐसा ही हश्र हुआ था. पूरे तीन महीने 'केरल कैथोलिक एसोसिएशन' ने बंबई के षणमुखानंद सभागार के सामने, जहां यह नाटक खेला जा रहा था, धरना दिया. एसोसिएशन को ईसा के मेरी मेग्डालने के साथ संबंध दिखाए जाने पर आपत्ति थी. उसने पात्रों पर अश्लीलता

नामस भोजानी

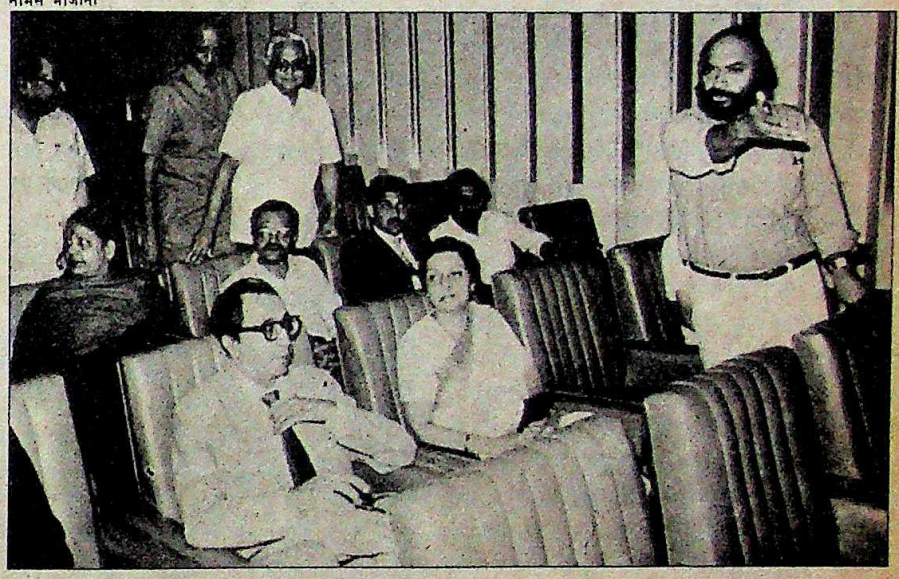

निहलाणी के साथ 'तमस' देखते जज

का आरोप लगाया. एक बार तो सभागार में बम रखने की भी धमकी दी गई. आखिरकार पिछले साल 27 फरवरी को शहर की दीवानी अदालत ने जनता में आक्रोश फैलने की संभावनाओं के मद्देनजर इसके प्रदर्शन पर रोक लगा दी.

नाटक ही नहीं, फिल्में भी इस धार्मिक संकीर्णता का शिकार हुई हैं. जून 1986 में जरतुश्त की जीवनी पर बनी साइरस भरूचा की फिल्म 'ऑन विंग्स ऑफ फायर' को भी कई रूढ़िवादी पारसियों के विरोध का सामना करना पड़ा. 'कौंसिल फॉर विजिलेंट पारसीज' के अध्यक्ष बी.के. मिस्त्री ने आरोप लगाया था, "यह फिल्म न तो ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है और न ही धर्मग्रंथों के अनुरूप. इसमें जरतुश्तवाद की गलत तस्वीर पेश की गई है."

हद तो यह कि पिछले वर्ष जून में शिवसेना महिला आघाडी के विरोध प्रदर्शनों के बाद दूरदर्शन द्वारा देर रात दिखाई जाने वाली फिल्में भी बंद कर देनी पड़ी थीं. इस संगठन की नेता बंबई के मेयर डॉ. रमेश प्रभु की पत्नी डॉ. पुष्पा प्रभु हैं. इस शृंखला में दूरदर्शन ने 'आक्रोश' और 'अर्धसत्य' सरीखी कुछ पुरस्कृत भारतीय और कुछ विदेशी कला फिल्में दिखाई थीं. पर प्रभु की दलील थी कि सेक्स और अश्लीलता से भरपूर ये फिल्में बच्चों को गुमराह करती हैं. इस पर दूरदर्शन ने इनका प्रसारण बंद कर दिया.

ये कट्टरपंथी गुट अक्सर अपने समुदाय का एक छोटा-सा भाग होने के बावजूद अपने कट्टर विचारों को पूरे समुदाय पर थोप देने में सफल हो जाते हैं. कई बार तो उन्होंने विवादास्पद नाटक या फिल्म को देखा तक नहीं होता. इन गुटों की हाल की सफलता को देखकर तो यही लगता है कि सरकारी सेंसर संस्थाएं अब जनता के मनोरंजन का निर्धारण करने वाली एकमात्र संस्थाएं नहीं रही हैं. फिल्म समीक्षक इकबाल मसूद भी मानते हैं, "सेंसरशिप के बिना गुजारा नहीं. जिन हालात से हमारा देश गुजर रहा है, उन्हें देखते हुए फिल्म निर्माताओं को ज्यादा छूट दिए जाने का खतरा मोल नहीं लिया जा सकता." लेकिन निहलाणी मानते हैं कि दर्शकों को प्रतिक्रिया जाहिर करने का पूरा हक है, "हमने जो दिखाया वह सही है या गलत इसका निर्णय दर्शकों पर ही छोड़ दें."

लेकिन कट्टरवादी गुट समाज की इसी स्वतंत्रता का गला घोंटने पर तुले हैं. 'तमस' दो वर्गों की लड़ाई में मील का पत्थर है. इसमें एक वर्ग मानता है कि जनता को सचाई जानने का अधिकार है, दूसरे वर्ग का मत है कि समाज को क्या जानना चाहिए यह तय करने का अधिकार गिने-चुने लोगों को ही है.

—सलिल त्रिपाठी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तमिलनाडु

सिंहासन के लिए संघर्ष

राष्ट्रपति शासन लागू होने से राजनैतिक अनिश्चितता

राजनीति में कोई हमेशा किसी का दोस्त नही होता और दुश्मनी के पैमाने भी वक्त-जरूरत के हिसाब से बदलते रहते हैं. तमिलनाडु में पिछले हफ्ते हुए राजनैतिक घटनाचक्र से एक बार फिर यह बात साबित हो गई है. सिर्फ 23 दिन पहले पार्टी के एक बड़े तबके के विरोध के बावजूद अपने दिवंगत पति की मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठी 64 वर्षीय वैकोम नारायणी जानकी रामचंद्रन को समर्थन देने के सवाल पर इंका जिस तरह आंखमिचौनी खेल रही थी और 28 जनवरी को उसने जिस ढंग से जानकी सरकार को ऐन मौके पर अंगूठा दिखा दिया उसी से आगे की घटनाएं स्पष्ट होने लगी थीं. और 30 जनवरी की शाम राज्यपाल सुंदरलाल खुराना की सिफारिश पर नई दिल्ली से तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लगाने और विधानसभा भंग करने की घोषणा के साथ अनहोनी राजनैतिक घटनाओं का यह सिलसिला पूरा हो गया. तमिलनाडु में वर्चस्व बनाए रखने की इच्छुक इंका के मंसूबे पूरे होने के साथ ही वहां आठ साल से चली आ रही स्थिरता को पलीता लगता दिख रहा है. द्रमुक अध्यक्ष एम. करुणानिधि ने इसे इंका के 'तख्ता पलटो खेल' की संज्ञा देते हुए कहा कि "एमजीआर को भारत रत्न देने के दो दिन बाद प्रधानमंत्री ने उनकी पार्टी की सरकार बर्खास्त करने का फैसला कर लिया."

1980 के लोकसभा चुनाव में द्रमुक-इंका गठजोड़ की कामयाबी के बाद फरवरी 1980 में एम.जी. रामचंद्रन की सरकार भी ऐसे ही बर्खास्त कर वहां राष्ट्रपति शासन लगाया था. अब एमजीआर की मौत के महीना भर बाद उनकी पत्नी के साथ भी यही किस्सा दुहराया गया. तब एमजीआर का विधानसभा में पूर्ण बहुमत था, जबकि राज्य में तीसरी दफा लगे इस राष्ट्रपति शासन के वक्त उनकी पत्नी जानकी विधानसभा में हुई अभूतपूर्व बारदातों के बाद सामान्य बहुमत पाने में ही सफल हो सकी थीं.

जानकी को मुख्यमंत्री बनने के अपने निर्णय पर शायद पछतावा हो रहा होगा. विधानसभा सत्र से कुछ दिन पहले 'इंडिया टुडे' के साथ अपनी पहली बातचीत में उन्होंने स्वीकार किया था, "दरअसल मैं संन्यास लेने की सोच रही थी. मैं चाहती थी कि रामवरम् गार्डन्स छोड़कर कोई छोटा मकान ले लूं और बाकी जीवन चैन से काटूं." लेकिन वे अपने को जयललिता के खिलाफ जहर उगलने से नहीं रोक पाई. फिर क्या था, सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो गया.

लेकिन जानकी सरकार ने जिस तरीके से विधानसभा में बहुमत साबित किया उसकी शायद किसी को उम्मीद भी नहीं थी. 28 जनवरी को पांडियन ने जब जानकी सरकार

प्रमोद पुष्करणा

राजीव से समर्थन मांगती जानकी

शुरू में इंका की चुप्पी का अर्थ यह लगाया जा रहा था कि वह जानकी को समर्थन देगी. बाद में उसने इरादा बदल दिया. फिर भी विधानसभा की कार्यवाही से जानकी की अल्पमत सरकार को अस्थायी जीवनदान मिल गया था

के बहुमत की घोषणा की तब 235 सदस्यों वाले सदन में आधे सदस्य भी मौजूद नहीं थे. जानकी के पक्ष में 99 मत और विपक्ष में 8 मत पड़े. तीन सदस्यों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया. (द्रमुक के 10 निष्कासित विधायकों को छोड़कर फिलहाल सदन की सदस्य संख्या 225 है). जयललिता गुट के प्रमुख नेता और पूर्व मंत्री एस. रामचंद्रन ने गुस्से में कहा, "यह विधानसभा सत्र नहीं, गैर-कानूनी बैठक थी."

28 जनवरी की सुबह 9.40 पर जब जानकी उदास मन से विधानसभा पहुंचीं तो लगता था कि अब उनका खेल खत्म हो गया है. इसके पहले 63 विधायकों वाली इंका की रहस्यमय चुप्पी का अर्थ यह लगाया जा रहा था कि वह जानकी को समर्थन देगी. लेकिन आखिरी मौके पर पार्टी ने विधानसभा में जानकी के खिलाफ मतदान का फैसला कर लिया. साफ लग रहा था कि जानकी गुट विधानसभा में हार जाएगा. इंका विधायकों के अलावा उसके खिलाफ जयललिता गुट के

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पीटीआइ

विधानसभा में घायल इंका विधायक

में से एक टी.आर. वेंकटरमनन ने बताया, "पार्टी का विचार अविभाजित अन्नाद्रमुक को समर्थन देने का था. लेकिन आलाकमान अब बेहयाई से इस रवैये को बदल रहा है." हालांकि इन विधायकों में से एक दुरई कृष्णमूर्ति ने अपने इस्तीफे की बात का खंडन किया. सदन स्थगित किए जाने के कारण विरोध भड़का उठा.

जानकी गुट ने विधानसभा स्थगित रहने के दो घंटे के इस आखिरी मौके को जाया नहीं होने दिया. इस दौरान वे अपने कमांडर वीरप्पन के नेतृत्व में द्रमुक, कम्युनिस्ट पार्टियों तथा जनता पार्टी के विधायकों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उन्हें फुसलाने की कोशिश में लगे रहे. द्रमुक अध्यक्ष करुणानिधि से भी टेलीफोन पर बातचीत की गई पर इस सब का नतीजा सिफर रहा.

दोपहर में पांडियन ने एक बार फिर एक

एस.के. चट्टा/टाइम्स ऑफ इंडिया

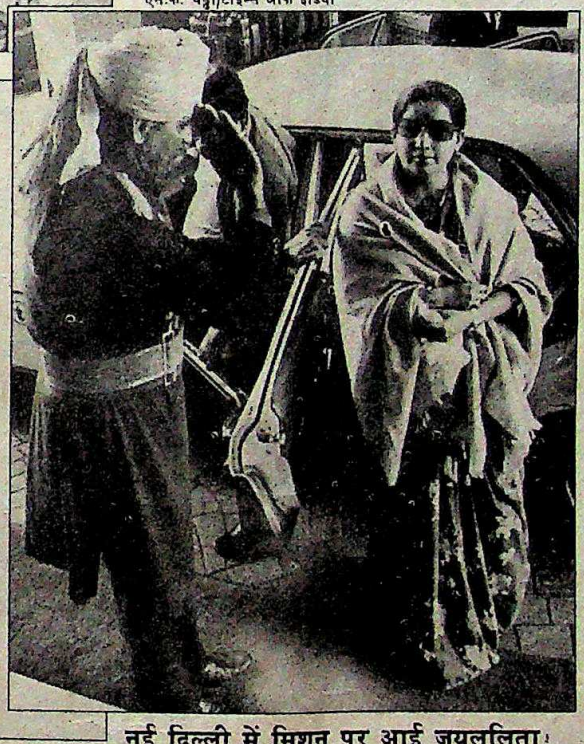

नई दिल्ली में मिशन पर आई जयललिता

सनसनीखेज़ घोषणा करके सदन की बैठक दुबारा स्थगित कर दी. इस बार उन्होंने जयललिता गुट के चार पूर्व मंत्रियों और अन्नाद्रमुक के मुख्यालय सचिव सी. अरंगनायकम की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की घोषणा की. तर्क यह दिया गया कि उन्होंने अन्नाद्रमुक के व्हिप का उल्लंघन करेंगे ऐसा बयान पहले ही दे डाला है. यह सब विपक्ष के लिए बर्दाश्त से बाहर की बात थी. विधानसभा में अध्यक्ष के पैनल में शामिल इंकाई विधायक एस. शिवरामन ने पांडियन की कुर्सी संभाल ली. उनकी अध्यक्षता में विधानसभा ने एक प्रस्ताव पास करके पांडियन को अध्यक्ष पद से हटा दिया.

आखिरकार दोपहर तीन बजे जब विधानसभा बैठी तब वे नेता भी मौजूद थे जिनकी सदस्यता पांडियन ने खत्म कर दी थी. उस समय पांडियन सदन में घुसे. पांडियन को देखते ही कुछ इंका विधायक उनकी तरफ लपके. नतीजतन उन्हें उलटे पैरों लौटना पड़ा. बाद में पांडियन ने कहा, "मुझे सदन से निकल आना पड़ा क्योंकि एक राष्ट्रीय पार्टी के एक सदस्य सीधे मेरी आंखों पर प्रहार करने चले आ रहे थे." इसके तुरंत बाद ही विधानसभा जंग का मैदान बन गई. जानकी गुट और इंकाई विधायक एक दूसरे पर पेपरवेट, चप्पलें, माइक और कुर्सियां तक फेंकने लगे. अध्यक्ष की कुर्सी नीचे फेंक दी गई और उनकी मेज को सदन के बीच में खींच लाया गया. जानकी समर्थक एक विधायक अपनी लुंगी ऊपर खोंसकर उस मेज पर चढ़ गए और इंकाई विधायकों को जोर-आजमाइश के लिए ललकारने लगे.

जल्दी ही हालत बदतर हो गई. बाहरी लोग, जिनमें ज्यादातर गुंडे थे, सदन में घुस आए और मारधाड़ तेज हो गई. तभी डंडे लहराती पुलिस विधानसभा में घुस आई और विधानसभा के अंदर किए गए लाठीचार्ज से 15 इंका विधायक घायल हो गए. इस हमले की अगुआई खुद शहर के पुलिस आयुक्त डब्लू.आई. देवरम कर रहे थे.

इसी अफरातफरी के बीच 15 मिनट बाद पांडियन ने सदन की कार्यवाही फिर शुरू कर दी. उन्होंने घोषणा की कि विश्वास प्रस्ताव मतदान के लिए सदन के पटल पर रखा जा रहा है. उस समय सदन में पांडियन को छोड़कर सिर्फ 110 विधायक ही मौजूद थे. द्रमुक के सदस्यों ने प्रस्ताव पर मतदान की मांग की. मतदान के दौरान जानकी गुट के 97 विधायकों और एक नामजद तथा फारवर्ड ब्लॉक के एक विधायक ने प्रस्ताव के समर्थन में वोट दिए. विधानसभा में मौजूद द्रमुक के आठ विधायकों ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिए. जनता पार्टी के एक विधायक और मुस्लिम लीग के दो विधायकों ने मतदान में भाग नहीं लिया. इसी के साथ अन्नाद्रमुक के सचेतक दुरई गोविंदराजन की मांग पर पांडियन ने जयललिता गुट के 27 विधायकों की सदस्यता दलबदल विरोधी कानून के तहत समाप्त कर दी.

अगर इंका के रवैये में आखिरी मौके पर बदलाव नहीं आता तो किस्सा कुछ और ही होता. इंका नेताओं का कहना है कि यह खबर

इंका ने पलटा शायद इसलिए खाया कि उसे भीड़ जुटाने की जयललिता की क्षमता का एहसास हो गया था. पार्टी हफ्तों पहले से न केवल जानकी की लोकप्रियता को आंक रही थी बल्कि मध्यावधि चुनावों में ताकत बढ़ाने की सोच रही थी

33, द्रमुक के 12, माकपा के चार, भाकपा के दो और रिपब्लिकन पार्टी तथा हिंदू देशम के एक-एक सदस्य को मिलाकर कुल 117 विधायक थे. फारवर्ड ब्लॉक के दो में से एक सदस्य ने भी विरोध का फैसला किया था.

सुबह दस बजे जब विधानसभा शुरू हुई तो पांडियन ने एक ज़बरदस्त धमाका किया. उन्होंने कहा कि पांच इंकाई विधायकों ने उन्हें सदन से अपने इस्तीफे की टेलीफोन से खबर दी है. इसके बाद उन्होंने दोपहर तक सदन की बैठक स्थगित कर दी. इन विधायकों

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लगते ही कि जानकी गुट इंका विधायकों को फुसलाने की कोशिश कर रहा है, पार्टी ने अचानक जानकी गुट की मुखालफ़त करने का फैसला कर लिया. समझा जाता है कि इस महत्वपूर्ण विधानसभा सत्र के दो दिन पहले इंका के लगभग 20 विधायकों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया गया था.

इसके सिर्फ एक दिन पहले ही पार्टी अध्यक्ष राजीव गांधी ने नई दिल्ली में अपने निवास पर बैठक बुलाकर कहा था कि जानकी सरकार बनी रहे, इसका बंदोबस्त किया जाए. उन्होंने मद्रास में पर्यवेक्षक का जिम्मा केरल के पूर्व मुख्यमंत्री के करुणाकरन और केंद्रीय गृहमंत्री बूटा सिंह को सौंप दिया था. यह भी तय हो गया था कि ये दोनों नेता इंका महासचिवों जी.के. मूपनार और केदारनाथ सिंह के साथ 27 जनवरी को विशेष विमान से मद्रास जाकर इंका विधायक दल की बैठक में मौजूद रहेंगे.

पर बूटा सिंह पांच कारों में लदे अपने कमांडो के साथ दिल्ली हवाई अड्डे पहुंचे ही थे कि उनके वायरलेस फोन की घंटी बज उठी. प्रधानमंत्री कार्यालय से संदेश था कि उन्हें दिल्ली नहीं छोड़नी है. हवाई अड्डे पर बूटा सिंह ने अपने पार्टी सहयोगियों से घर लौटने को कहा और इसके साथ ही इंका का रुख़ बदलने का नाटक शुरू हो गया.

गृहमंत्री ने मद्रास बात करके जानकी को चेतावनी दी कि यदि इंका विधायकों को फुसलाने की खबरें सही पाई गईं तो उनकी पार्टी के लिए अपने वादे पर कायम रहना मुश्किल हो जाएगा. इस बीच राजीव ने केदारनाथ सिंह को ऐसा बयान जारी करने का निर्देश दिया जिसमें कोई वचन न दिया गया हो. बयान में कहा गया था कि इंका अविभाजित अन्नाद्रमुक को समर्थन देती रहेगी. इंका अध्यक्ष की तरफ से आया यह बयान किसी फैसले तक पहुंचने का समय लेने के लिए था. आखिरकार 27 जनवरी को करीब आधी रात मेघालय से बूटा सिंह को संदेश मिला कि पार्टी को जानकी सरकार के खिलाफ वोट देना है.

यह खबर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया तक पहुंचाने का जिम्मा एक महासचिव को सौंपा गया. पर तब तक इतनी देर हो चुकी थी कि अगली सुबह प्रकाशित होने वाले ज्यादातर अखबार यह खबर छाप नहीं पाए. केदारनाथ सिंह ने कहा, "इंका के सामने दो विकल्प थे. या तो वह संयुक्त अन्नाद्रमुक को समर्थन दे या नए चुनावों की मांग करे." कई गंभीर कोशिशों के बावजूद दोनों धड़ों को एक दूसरे के करीब लाना मुमकिन नहीं हो पाया था. ऐसी हालत में कोई और

पीटीआइ

विधानसभा परिसर में डंडे बरसाती पुलिस; और (दाएं) पांडियन: शर्मनाक

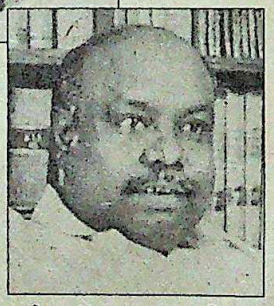

फैसला करने का मतलब होता—लोकतंत्र का मजाक उड़वाना, अस्थिरता तथा मौकापरस्त गठबंधनों को बढ़ावा देना:"

इंका का रुख इसलिए बदला कि कि वह गलत घोड़े पर नंबर लगा रही है. हफ्तों पहले से ही पार्टी सिर्फ जानकी की लोकप्रियता को ही आंक नहीं रही थी बल्कि मध्यावधि चुनावों में अपनी ताकत बढ़ाने की संभावना पर भी गौर कर रही थी. गुप्तचर एजेंसियों के साथ-साथ इंका के कार्यकर्ता भी कहने लगे थे कि भीड़ जुटाने की जयललिता की क्षमता अन्नाद्रमुक में उनकी प्रतिद्वंद्वी से कहीं ज्यादा है.

तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक की पीठ पर सवारी करके अपने लिए जगह बनाने वाली इंका की कोशिश हरदम यही रही है कि अन्नाद्रमुक दोफाड़ न होने पाए. इसीलिए राजीव ने जानकी और जयललिता दोनों से कहा था कि वे चाहेंगे कि दोनों धड़े अपने मतभेद दूर कर लें. जानकी ने दिल्ली से वापस आते ही एकता की अपील जारी भी की पर जयललिता ने इसे ठुकरा दिया.

पर जानकी की इंका में नजदीकी बढ़ते ही उनके सूत्रधार वीरप्पन बेचैन हो गए क्योंकि इससे उन पर जानकी की निर्भरता कम हो जाती. यही वजह थी कि उन्होंने इंका विधायकों को फुसलाकर अपने समर्थन में जुटाने की कोशिश की. केदारनाथ सिंह कहते हैं, "वीरप्पन जानकी को आश्रित मुख्यमंत्री बनाए रखना चाहते थे. वे हमारी पार्टी के लिए परेशानियां पैदा कर रहे थे."

इसके अलावा मूपनार के नेतृत्व वाला असरदार गुट महसूस करता था कि तमिलनाडु में मध्यावधि चुनाव कराना इंका के फायदे में रहेगा क्योंकि अन्नाद्रमुक और द्रमुक दोनों की ही हालत खस्ता हो चुकी है. हकीकत तो यह है कि एमजीआर के मरते ही इंका ने उनके वोट बैंक पर दावा जताना शुरू कर दिया था. एमजीआर की मृत्यु के बाद राष्ट्रीय शोक की घोषणा और उन्हें मरणोपरांत 'भारत रत्न' अलंकरण दिया जाना इसी दिशा में उठाए गए कदम थे.

इंका के फैसले से यदि जानकी सरकार लड़खड़ा गई है तो इससे राष्ट्रीय दल के रूप में उसने अपने लिए भी समस्याएं खड़ी कर ली हैं. इस घटनाक्रम से नाराज तमिलनाडु में इंका के नेता और फिल्म अभिनेता शिवाजी गणेशन ने पार्टी छोड़ने की धमकी दी है. उनसे इसके पहले कई बार राजीव गांधी सलाह-मशविरा कर चुके हैं. चार विधायकों के इस्तीफे से भी पार्टी को बड़ा धक्का लगा.

दूसरे स्तर पर, अगर जानकी सरकार गिर जाती है तो इसका मतलब होगा कि भारत-श्रीलंका समझौते के मामले में नई दिल्ली का समर्थन करने वाली एक सरकार को खो देना. श्रीलंका से भारतीय शांति सेना की वापसी के लिए विपक्षी द्रमुक द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन ने यदि जोर पकड़ लिया तो इंका को तमिलों की भावनाओं पर नियंत्रण रख पाना मुश्किल हो जाएगा.

इंका के लिए राज्य की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने के मोह पर काबू पाना निश्चय ही बहुत मुश्किल है. गुटबाजी से ग्रस्त प्रदेश इंका के पास कोई करिश्माई नेता नहीं है. इसलिए तमिलनाडु में बड़े भाई की भूमिका निभाने के चक्कर में इंका अगर अपना माध्यम बदल ले तो किसी को अचंभा नहीं होना चाहिए. पार्टी यहां अब शायद एमजीआर के बजाय जयललिता का हाथ थामकर राजनीति करेगी.

—प्रभु चावला और एस.एच. वेंकटरमनी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मज़ा आ गया

क्रिस
लाईम सोप

K-2H-87

ताज़गी का संदेशा लिये एक नई बहार आई है।
क्रिस लाईम सोप। नींबू की प्यारी सुगँध। मन में
उभरती हुई खुशी। क्रिस लाईम सोप से नहा कर तो देखिये।
आप कह उठेंगे, 'मज़ा आ गया!'

A Kusum Product
विश्वास के साथ खरीदिये

नींबू की महकती ताज़गी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हरियाणा

दिखावटी बदल

चौटाला की ताकत ही बढ़ी

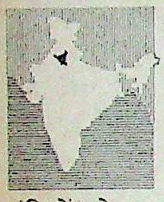

हाल में हुआ हरियाणा मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह पिछले समारोहों से काफी अलग था. छह महीनों में यह ऐसा तीसरा समारोह था. पर 17 मंत्रियों को शपथ दिलाते वक्त पहले की तरह न तो उत्साही समर्थक मौजूद थे और न ही कोई नारेबाजी हो रही थी.

मुख्यमंत्री देवीलाल के दो बेटों की कशमकश से पार्टी में जैसी गुटबंदी फैली उसके कारण हरियाणा के सभी 22 मंत्रियों ने अपने इस्तीफे इस शपथ ग्रहण समारोह के ठीक नौ दिन पहले 16 जनवरी को मुख्यमंत्री देवीलाल को सौंप दिए थे.

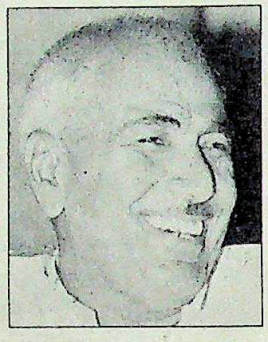

चौटालाः पिता के प्यारे

नए मंत्रिमंडल के बारे में इतनी ज्यादा गोपनीयता बरती गई कि उपमुख्यमंत्री बनारसीदास गुप्ता भी संभावित रद्दोबदल के बारे में आखिरी मिनट तक कोई खबर नहीं पा सके. जानकार सूत्र इसकी दो वजहें बताते हैं. पहली तो यह कि देवीलाल कम-से-कम तीन कैबिनेट मंत्रियों की छुट्टी करने का मन बना चुके थे पर आखिरी वक्त में उन्होंने अपना इरादा बदल दिया. दूसरे, उन्होंने अपने सभी मंत्रियों को जानबूझकर इसलिए अंधेरे में रखा क्योंकि वे उन्हें यह जता देना चाहते थे कि उनके राजनैतिक भविष्य का सारा दारोमदार उन्हीं के ऊपर है.

ऊपर से तो रद्दोबदल कोई खास नजर नहीं आता. मंत्रिमंडल से विदा किए गए अकेले कैबिनेट मंत्री परमानंद का कोई खास असर नहीं है. उनकी जगह लाई गई भाजपा की सुषमा स्वराज भी राज्य में कोई बड़ी राजनैतिक हैसियत नहीं रखतीं. इसी तरह हटाए गए पांच राज्यमंत्रियों का भी खास सियासी रसूख नहीं है.

फिर भी देवीलाल ने उन्हें संतुष्ट करने की कोई कसर बाकी नहीं रखी. हटाए गए राज्यमंत्रियों में से तीन—नर सिंह, महा सिंह और सीताराम सिंगला को सरकारी बोर्डों का अध्यक्ष बना दिया गया. बचे हुए दो पूर्व राज्यमंत्रियों—मनफूल सिंह और नरबीर सिंह को भी इसी तरह का मुआवजा मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है.

कैबिनेट मंत्री का दर्जा पाए पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रणबीर सिंह मान को राजनैतिक दृष्टि से एक महत्वहीन पद — राज्य शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष—दे दिया गया है. मंत्रिमंडल में उनके उत्तराधिकारी धीरपाल सिंह कोई बड़ी हस्ती नहीं हैं. बाकी तमाम मंत्रियों को उनके महकमों में मामूली फेरबदल करने के बाद बरकरार रखा गया है.

लगता है देवीलाल ने इस्तीफों और ज्यादातर मंत्रियों की फिर बहाली का यह नाटक अपनी ताकत दिखाने के लिए ही रचा था. उन्होंने यह आभास देने की कोशिश की है कि समूचे मंत्रिमंडल द्वारा इस्तीफा देकर उनमें समर्थन जताने से उनके दोनों बेटों—चौटाला और रणजीत सिंह—के पर कट गए हैं.

हालांकि उत्तराधिकार की यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई पर देवीलाल ने फिलहाल दोनों भाइयों का मसला जरूर सुलटा लिया है. देवीलाल के परिवार के करीबी सूत्रों का कहना है कि इस तरह उन्होंने चौटाला की ताकत पर ही मुहर लगाई है. फेरबदल से साफ लगता है कि चौटाला अब पहले से कहीं और ताकतवर हो गए हैं. जैसेः—

- रणजीत समर्थक राज्यमंत्रियों की छुट्टी.
- उनके मुख्य समर्थक और प्रदेश लोकदल अध्यक्ष पद के दावेदार मान दरकिनार.
- रणजीत का आदमी माने जाने वाले देवीलाल के अतिरिक्त राजनैतिक सचिव सतवीर नेहरा की छुट्टी.
- चौटाला के खासमखास धरमवीर को एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री का अपमान करने का आरोप होने के बावजूद सरकार में बरकरार रखा जाना.
- प्रदेश पार्टी अध्यक्ष को वरिष्ठ मंत्रियों के ऊपर तवज्जो देने के लिए पहले उपमुख्यमंत्री का पद समाप्त कर देना. हालांकि गुप्ता को अब फिर से उपमुख्यमंत्री बना दिया गया है.

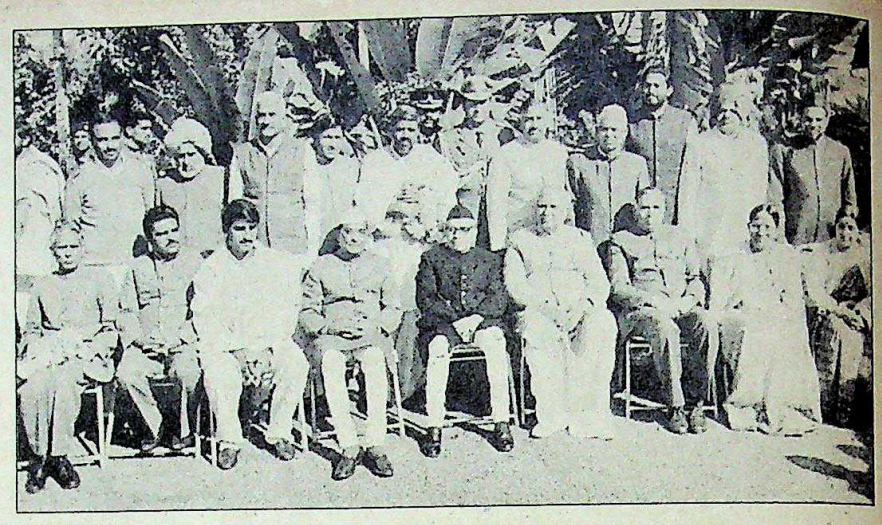

शपथ ग्रहण समारोह के बाद हरियाणा का नया मंत्रिमंडल

बताया जाता है कि मुख्यमंत्री ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमवतीनंदन बहुगुणा से यह आग्रह भी किया है कि चौटाला जब तक अध्यक्ष नहीं बन जाते तब तक उनको पार्टी की राष्ट्रीय समिति में जगह दे दी जाए.

इन उपलब्धियों के बाद चौटाला, भविष्य में उन्हें चुनौती दे सकने वाले वरिष्ठ मंत्रियों की ओर अपनी टेढ़ी निगाहें घुमा सकते हैं. सिंचाई और ऊर्जामंत्री बीरेंद्र सिंह, उद्योगमंत्री कृपाराम पूनिया और पूर्व उपमुख्यमंत्री बनारसीदास गुप्ता उनका अगला निशाना हो सकते हैं. अब तो आम तौर पर यह माना जाने लगा है कि इन तीनों ने ही मान के साथ मिलकर चौटाला विरोधी अभियान की अगुआई की थी.

रणजीत सिंह द्वारा बड़े भाई का वर्चस्व स्वीकार करने के बाद चौटाला विरोधी खेमे में ऐसा कोई नेता नहीं बचा जो उनका खुलेआम विरोध कर सके. इसलिए हो सकता है कि मुख्यमंत्री के सबसे बड़े बेटे अपने विरोधियों के कमजोरी का फायदा उठाकर उनसे एक-एक करके हिसाब चुकता कर लें. मान के साथ जो कुछ हुआ उससे तो यही झलक मिलती है.

—विपुल मुद्गल

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मेघालय

जातीय हिंसा से जलावतन

खासी आदिवासियों के आंदोलन से नेपालियों की दुर्दशा

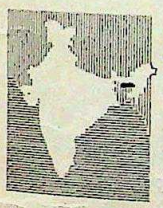

अधिकांशतः खासी वनवासियों द्वारा शुरू की गई जातीय हिंसा ने छह महीने से मेघालय को लपेट में ले रखा है. वनवासी आंदोलन के मुख्य शिकार नेपालियों की दुर्दशा पिछले पखवाड़े की एक घटना से उजागर हुई. शिलंग में राज्य सरकार नेपालियों के एक कब्रिस्तान को बड़ी तेजी से साफ करा रही थी. उस पर वह 2,500 नेपाली शरणार्थियों के लिए शेड बनवाने की सोच रही थी. उसे उम्मीद थी कि ये शेड महीने के आखिर तक तैयार हो जाएंगे. लेकिन नेपाली लोग इसे बहरी सरकार की बेरुखी का प्रतीक मानते हैं. 35 वर्षीय एक नेपाली प्रोफेसर मणि कुमार सुब्बा सवाल उठाते हैं, "क्या ऐसा नहीं लगता जैसे हमें जिंदा ही कब्रिस्तान में ले जाया जा रहा है?"

अब संकट के कगार पर पहुंच चुके ये जातीय झगड़े जुलाई 1986 के आसपास शुरू हुए जब खासी स्टुडेंट्स यूनियन (केएसयू) ने विदेशियों के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा. इसका निशाना राज्य के 75,000 नेपाली बने. पीढ़ी-दर-पीढ़ी से वे राज्य में रहते आए हैं और 14 लाख वनवासियों के लिए कभी खतरा नहीं माने गए. इससे आंदोलन के पीछे राजनैतिक स्वार्थ की गंध आती है. जल्दी ही होने वाले चुनावों के मद्देनजर केएसयू का ख्याल था कि ऑल

कब्रिस्तान पर शरणस्थल का निर्माण

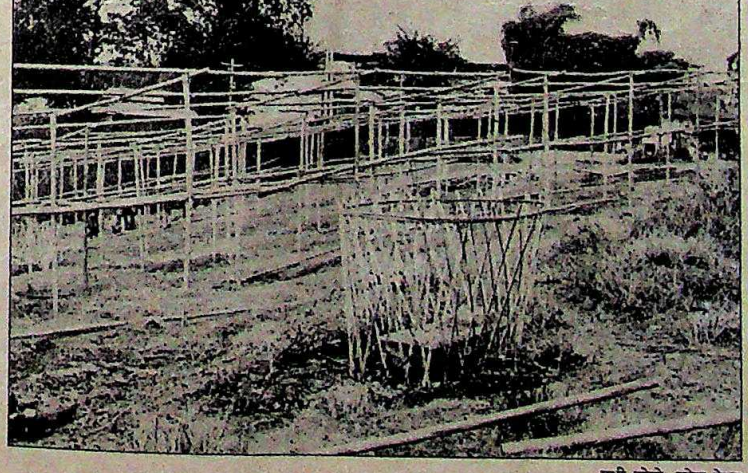

सभी फोटो: रमेश मेनन

शिलंग में नेपाली शरणार्थी: अधर में

असम स्टुडेंट्स यूनियन की तरह वह भी गैर-वनवासियों के खिलाफ वनवासियों के जज्बात भड़का सकती है और फिर आंदोलन की नैया पर सवार होकर सत्ता पर काबिज हो सकती है.

केएसयू अध्यक्ष बुल लिंगडोह कहते हैं, "हम मेघालय को फिजी या त्रिपुरा नहीं बनने देना चाहते." केएसयू का प्रचार था कि मेघालय एक और त्रिपुरा बनने जा रहा है जहां बंगालियों का प्रभुत्व हो जाने से वनवासी अल्पसंख्यक बन गए हैं. इससे आंदोलन भड़क उठा.

विदेशियों के विरुद्ध आंदोलन से इंका सरकार विकट स्थिति में फंस गई. कड़ी कार्रवाई से कहीं वनवासियों की भावनाओं को ठेस न पहुंचे और फलस्वरूप 2 फरवरी को हो रहे चुनावों में कोई उलटा असर न पड़े, इस डर से राज्य सरकार ने इस मुद्दे के प्रति सख्त रुख अख्तियार नहीं किया. मुख्यमंत्री विलियमसन संगमा कहते हैं कि मेघालय में इस समय हालांकि विदेशियों की कोई वास्तविक समस्या नहीं है पर राज्य में बांग्लादेशियों और नेपालियों की घुसपैठ रोकी नहीं गई तो मामला गंभीर होगा.

वनवासियों का आंदोलन ज्यों-ज्यों हिंसात्मक होता गया, संगमा सरकार ने कानून व व्यवस्था बहाल करने और इस तरह गैर-वनवासियों को आश्वस्त करने के लिए कड़े कदम उठाने के बजाय केएसयू की गतिविधियों के प्रति आंखें मूंदे रखी. नेपालियों पर हमले करके उन्हें घरों से भगा दिया गया, उनके मवेशी लूट लिए गए और मकानों को आग लगा दी गई. राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं ने तो अधिकारियों द्वारा आंदोलन दबाने के प्रयासों का भी विरोध किया. प्रशासन चरमरा गया.

वस्तुतः सरकार की सरपरस्ती पाकर केएसयू ने नेपालियों में आतंक फैलाकर उन्हें शरणार्थी शिविरों में पनाह लेने पर मजबूर कर दिया. पिछले साल एक समय तो शिलंग के 17 शिविरों में 10,000 से भी अधिक शरणार्थी थे. करीब 15,000 ने तो राज्य छोड़ दिया और कई भागकर नेपाल चले गए. हालांकि नेपाल ने करीब 7,000 लोगों के लिए शरणार्थी शिविर खोले पर उसने यह

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भी स्पष्ट कर दिया कि वह 'नेपाली भारतीयों' को नागरिकता नहीं देगा. असम सरकार ने भी इन शरणार्थियों को लेने में कोई रुचि नहीं दिखाई.

गैर-वनवासियों के विरुद्ध आंदोलन नवंबर के अंत तक जारी रहा. पांच महीने के रात्रि कर्फ्यू के बाद शिलंग में सामान्य स्थिति बहाल हो सकी. कर्फ्यू हटा लिया गया. लेकिन छह शिविरों में 4,000 नेपाली अभी भी अमानवीय हालात में जी रहे हैं. सबसे बुरा पहलू तो यह है कि अधिकांश नेपालियों के पास लौटने के लिए कोई घर भी नहीं बचा है, दंगाइयों ने घर भी जला दिए हैं. उनके पास रोजी-रोटी कमाने का कोई साधन नहीं बचा है.

नेपाली समुदाय के लोगों को दंगों में भारी आर्थिक नुकसान हुआ, पर राज्य सरकार ने एक भी दंगापीड़ित को एक पैसे का मुआवजा नहीं दिया. शिलंग में 20 लाख रुपए की लागत से नया शिविर बनाने के मामले में राज्य सरकार ने अपना भेदभावपूर्ण रवैया स्पष्ट कर दिया. यहां वे शरणार्थी रहेंगे जो अभी तक स्कूल-कॉलेजों की इमारतों में पड़े थे.

पांच बच्चों के साथ एक शिविर में रहने वाली 30 वर्षीया दिलमाया छेत्री कहती हैं, "क्या हम लोग सारा जीवन शिविरों में ही रहने को अभिशप्त हैं." सिर्फ गरीब नेपाली ही इन सबसे प्रभावित नहीं हुए हैं. शिलंग के कॉलेज में पढ़ाने वाले नर बहादुर राय ने जब अपने इलाके में केएसयू के लोगों को लूटमार करते देखा तो वे भाग कर गोरखा पाठशाला शरणार्थी शिविर में आ गए.

इन लोगों का भविष्य निश्चित रूप से अंधकारमय दिखता है. अनेक शरणार्थी किराये की झोंपड़ियों में रहते थे और इस बात की संभावना कम ही है कि उन्हें फिर ये झोंपड़ियां मिल पाएंगी. स्थानीय लोगों के दबाव की वजह से ऐसा नहीं हो सकेगा. जहां ऐसे घर दिए भी गए, वहां से गैर-वनवासियों को हटाने के लिए दबाव पड़ा. असुरक्षा के माहौल के कारण गैर-वनवासी इलाकों में कोई भी नेपाली शरणार्थी टिक नहीं सकता. अनेक गैर-वनवासी इलाकों से भाग चुके हैं.

आंदोलन के आर्थिक दुष्प्रभाव भी सामने आने लगे हैं. नेपाली दूध बेचने वाले लोग खासियों के हाथ अपनी गायें बेचकर भागने लगे हैं, सो दूध की कमी हो गई है. दूध की कीमत दुगनी होकर छह रुपए प्रति लीटर हो गई है. राज्य भर के किसानों को खाद की कमी होने लगी है. अब खाद उलटे-सीधे दामों पर असम से बैलगाड़ियों में लानी पड़ती है. खेत में काम करने या लकड़ी की ढुलाई करने वाले मजदूरों की किल्लत हो गई है. मेघालय के निजी कोयला खान मालिकों का काम करना मुश्किल हो गया है. उन्हें सस्ते नेपाली मजदूर नहीं मिलते.

राज्य सरकार ने जिस तरह का व्यवहार किया है, उससे वनवासी सख्त नाराज हैं. मुख्यमंत्री संगमा मानते हैं कि शिविरों में छह महीने गुजारना बहुत है और शरणार्थियों को वापस जाने में मदद की जानी चाहिए. लेकिन, वे कहते हैं, "इसके लिए माहौल बनाया जाना चाहिए और कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं किया जाना चाहिए." इस तरह नेपाली अब भी असुविधा भरे और अस्वास्थ्यकर शिविरों में पड़े हैं और उलटी-सीधी चीजें खाकर गुजर कर रहे हैं. अपुष्ट खबरों के अनुसार दर्जनों लोग बीमारियों से मर गए हैं.

वनवासियों द्वारा नेपालियों के खिलाफ चलाया जा रहा यह अभियान 1950 की भारत-नेपाल संधि का उल्लंघन है. इस संधि के अनुसार दोनों देशों के लोग एक-दूसरे के यहां जाने और रोजगार करने के लिए स्वतंत्र हैं. इंका के एकमात्र नेपाली विधायक डी.एन. जोशी कहते हैं, "हम लोग कैसे विदेशी कहलाएंगे? क्या हमने इन वर्षों में देश के विकास में योगदान नहीं किया?" जोशी का परिवार मेघालय में 1865 से ही है. अधिकांश नेपाली राज्य की सामाजिक मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं. शिलंग से 45 किमी दूर स्थित मावसिनरम में अपना घर जलाए जाने के बाद भागे 30 वर्षीय विष्णु गुरूंग कहते हैं कि राहत शिविर में उनके बच्चे नेपाली बोलना सीख रहे हैं. अभी तक उन्हें सिर्फ खासी भाषा का ही ज्ञान था. इसके अलावा राज्य के नेपालियों ने पिछले साल गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट (जीएनएलएफ) की राज्य शाखा को प्रतिबंधित करके वनवासियों को खुश करने की चेष्टा की. इस शाखा की स्थापना 1986 के आखिर में अमरीश थापा के नेतृत्व में कुछ लड़कों ने की थी. जातीय हिंसा भड़काने के बाद 34 नेपाली संगठनों ने सुभाष घीसिंग को पत्र लिखकर उनके आंदोलन से नाता तोड़ने की सूचना दी.

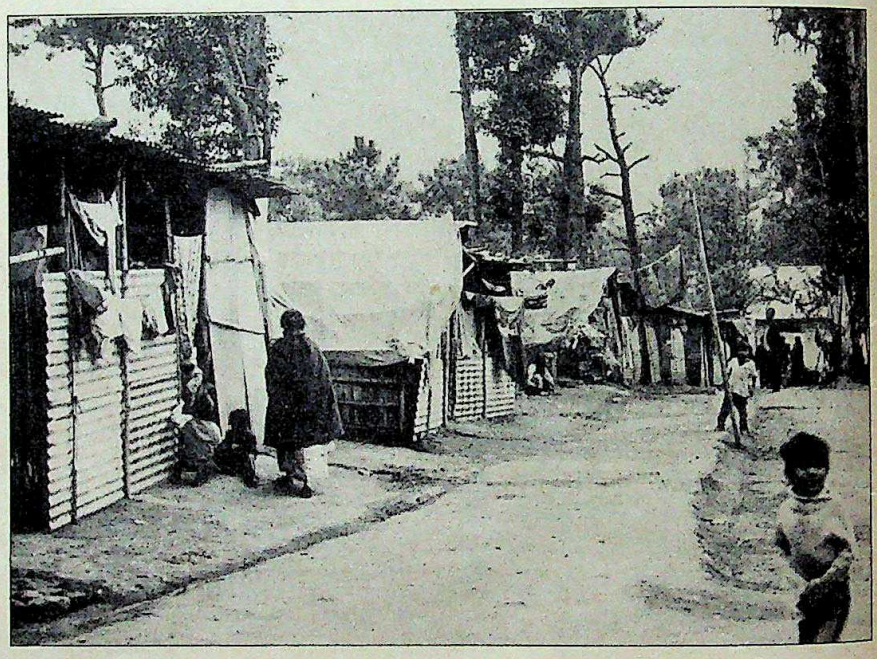

शरणार्थी शिविर: बदहाल जीवन

मुख्यमंत्री संगमा मानते हैं कि केएसयू के आंदोलन से दोनों समुदायों के बीच खाई पैदा हुई है. उन्हें उम्मीद है कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद शांति हो जाएगी. पर शिलंग की हाल की घटनाएं उनके इस दावे को झुठलाती हैं. एक नेपाली ईसाई का अंतिम संस्कार करने के बाद उसका ताबूत कब्र में डाला जा रहा था कि स्थानीय नौजवानों की टोली पहुंच गई और किसी नेपाली को वहां दफनाने पर आपत्ति की. उन्होंने कब्र पर थूका और धमकी दी कि वे बाद में लाश उखाड़ फेंकेंगे. डरे हुए रिश्तेदार शव को घर वापस ले गए और इसे किसी और कब्रगाह में दफनाया. अफसोस की बात तो यह है कि मृतक राज्य के पूर्व बैडमिंटन और टेबल टेनिस चैंपियन फुलमाया के पिता थे.

—रमेश मेनन, शिलंग में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बोहरा समुदाय

फतवे का खौफ

सूद न लेने के निर्देश पर विवाद

दाऊदी बोहरा समुदाय के 76 वर्षीय धार्मिक मुखिया सैयदना मुहम्मद बुरहानुद्दीन के एक फतवे से दुनिया भर में फैले कट्टरपंथी शिया मुसलमानों में एक बार फिर खलबली मच गई है. पिछले महीने सैयदना के बंबई (यहां जमात का मुख्यालय भी है) से कलकत्ता रवाना होने से कुछ ही दिन पहले विभिन्न शहरों की स्थानीय जमातों ने बोहरा मुसलमानों को निर्देश जारी किए कि वे अपने सभी बैंक खातों और दीगर जगह निवेश की गई रकम का ब्यौरा दें और ब्याज नहीं लेंगे इस आशय के हलफनामे पर दस्तखत करें. बोहराओं को ये फार्म पखवाड़े भर के भीतर भरकर देने को कहा गया था. अधिकांश बोहरा व्यवसायी हैं और उनका व्यवसाय बैंकों के ही बूते चलता है. सैयदना के आधे से ज्यादा अनुयायी भारत में ही हैं. बंबई में उनकी संख्या सबसे ज्यादा लगभग 70 हजार है.

करीब छह साल पहले भी सैयदना ने अपने अनुयायियों को बंबई मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक से जमा राशि लौटा लेने का हुक्म देकर शहर में खासी खलबली मचा दी थी. क्योंकि इस बैंक को चलाने वाले बोहरा समुदाय के ही लोग थे. लेकिन सैयदना के कट्टर अनुयायियों द्वारा बैंक के आगे धरना दिए जाने के बावजूद यह आंदोलन नाकाम रहा. लोगों को शुबहा था कि इस आंदोलन का असल मकसद अच्छे-खासे बैंक का नियंत्रण छीनकर सैयदना और उनके ही परिवार के लोगों के हाथ में रखना है.

लेकिन इस बार सैयदना ने बड़े पैमाने पर आह्वान किया है. दरअसल यह अभियान उन्होंने पिछले साल दिसंबर में पाकिस्तान के अपने दौरे के समय ही छेड़ दिया था. लेखक और बोहरा समुदाय के जाने-माने सुधारक असगर अली इंजीनियर के मुताबिक यह फतवा उपमहाद्वीप के मुस्लिम कट्टरपंथियों को खुश करने की एक कोशिश है. लेकिन विडंबना है कि ईरान के अलावा सभी मुस्लिम देशों में मुसलमान लाभ की सहभागिता के सिद्धांत पर काम करने वाले इस्लामी बैंकों या ब्याज देने वाले परंपरागत बैंकों में किसी को चुन सकते हैं.

इसके अलावा सैयदना ने एक बार फिर बोहरा महिलाओं को बुरका पहनने और मरदों को दाढ़ी बढ़ाने और कपड़े की परंपरागत टोपी पहनने को बाध्य करने का अभियान छेड़ दिया है. जाति बहिष्कार के डर से पहले इस अभियान को आंशिक सफलता मिली थी. लेकिन ब्याज पर प्रतिबंध से लगता है बोहरा लोग बेनामी खाते खोलने को ही मजबूर होंगे ताकि वे अपना व्यवसाय जारी रख सकें. समुदाय के भीतर कड़े विरोध और रोष को देखते हुए फार्म भरने की अवधि एक पखवाड़े से बढ़ाकर दो महीने कर दी गई है. इंजीनियर सवाल उठाते हैं, "हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश में सरकार एक व्यक्ति को संविधानेतर सत्ता बनने की छूट कैसे दे सकती है?"

सुधारवादियों ने जहां सैयदना के इस फतवे की नैतिकता और वैधता को चुनौती दी है, वहीं बंबई के मुस्लिम-बहुल क्षेत्रों में

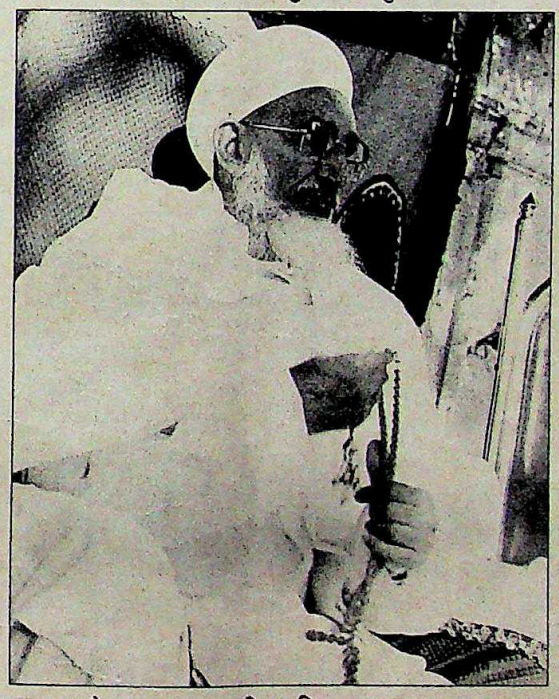

सैयदना बुरहानुद्दीनः विवादास्पद फतवा

लगे पोस्टरों में सैयदना और उनके परिवार के लोगों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने बैंकों और कंपनियों में भारी रकम लगा रखी है. बताया जाता है कि सैयदना परिवार के पास बहुत धन है. बोहरा समुदाय की धार्मिक कर प्रणाली पर उसका नियंत्रण है. इसके अलावा उन्हें भेंट में भी धन मिलता है जिसका सिलसिला बोहरा शिशु के पैदा होने से पहले शुरू हो जाता है और मृत्यु के बाद तक चलता है.

समुदाय से उगाहा गया धन या तो सैयदना परिवार के या बोहरा समुदाय के सैकड़ों ट्रस्टों में से एक के नियंत्रण में है. इन सब ट्रस्टों के एकमात्र ट्रस्टी सैयदना हैं. (बंबई में ही धर्मादा आयुक्त के दफ्तर में ऐसे 235 रजिस्टर्ड ट्रस्ट हैं). इन ट्रस्टों की सालाना आय का ठीक अंदाजा नहीं लगाया जा सकता. सुधारवादियों के एक अनुमान के अनुसार यह राशि करीब 20 करोड़ रुपए है. जबकि एक खुफिया अधिकारी के अनुसार यह लगभग 16 करोड़ रुपए बैठती है. समुदाय के कुछ प्रमुख सदस्य इसे दस करोड़ के आसपास आंकते हैं. लेकिन इतना निश्चित है कि इस धन का एक बड़ा भाग सैयदना और उनके परिवार के करीब 250 सदस्यों के नियंत्रण में है. इनमें से अधिकांश लोग बंबई में मालाबार हिल क्षेत्र के सैफी महल एनक्लेव में रहते हैं. धार्मिक करों से होने वाली आय के अलावा परिवार के पास काफी अचल संपत्ति भी है. अनेक कंपनियों में भी उनके शेयर हैं.

परिवार के लोगों द्वारा इस कदर धन-दौलत जमा करने और बोहरा लोगों को एक लड़ी में पिरोने का श्रेय पूर्व सैयदना ताहिर सैफुद्दीन को है. वे एक तेजतर्रार धार्मिक मुखिया थे जिन्होंने 1965 में अपनी मौत से काफी पहले अपने बेटे को उत्तराधिकारी मुकर्रर कर दिया था. सैफुद्दीन की चार पत्नियों से 12 बेटे और नौ बेटियां पैदा हुईं. मौजूदा सैयदना उनकी पहली पत्नी के सबसे बड़े पुत्र हैं.

हालांकि अब इस परिवार में मुखिया पद के कई दावेदार हैं पर सैयदना बुरहानुद्दीन ने अभी तक अपना उत्तराधिकारी नामजद नहीं किया है. कई वर्षों तक उनके एक सौतेले भाई युसुफ नज्मुद्दीन को इस पद का अगला दावेदार माना जाता रहा. लेकिन पिछले साल उनके निधन के बाद से सैयदना के तीन सौतेले भाई उनके करीबी सलाहकार बन गए बताए जाते हैं. कुछ सुधारवादियों का कहना है कि इस नए सलाहकार गुट ने ही सैयदना को उपमहाद्वीप में फैली कट्टरता की लहर का फायदा उठाने के लिए राजी किया है ताकि सैयदना इस्लाम के एक पक्के धार्मिक मुखिया का दावा पेश कर सकें.

बोहरा समुदाय के सामाजिक मूल्य भले ही मध्ययुग के हों, आर्थिक दृष्टि से तो वे व्यापार और अर्थव्यवस्था की आधुनिक दुनिया से ही जुड़े हुए हैं. नए फतवे के कारण समुदाय को अपने आर्थिक हितों की बलि चढ़ानी होगी.

—एम. रहमान

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

महाराष्ट्र

सपना रहा सपना

नेहरू के आदर्शों से मजाक

करोड़ों रुपए की लागत से तैयार नेहरू केंद्र की गोलाकार मीनार अब बंबई का विशेष चिन्ह बन गई है. लेकिन यहां आने वाले दर्शक देश के पहले प्रधानमंत्री की याद में बनी इस भारी-भरकम इमारत के सूनेपन को महसूस किए बिना नहीं रह सकते. 'डिस्कवरी ऑफ इंडिया हॉल' नामक इस तिमंजिली इमारत को बने हालांकि दो साल से ज्यादा बीत चुके हैं पर अधिकारी अभी तक इसे 'नेहरू के सपनों के भारत' के अनुरूप संग्रहालय का रूप दे पाने में बुरी तरह असफल रहे हैं.

इसी निकम्मेपन के चलते नेहरू केंद्र अब एक बार फिर विवाद का मुद्दा बन गया है. मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण की अध्यक्षता में केंद्र की कार्यकारिणी समिति ने दो बैठकें करने के बाद अपने चार वर्ष पुराने प्रकाशन 'साइंस एज' को एक निजी प्रकाशक को सौंपने का फैसला कर लिया. इससे संस्थान को 60 लाख रुपए का घाटा हो चुका है.

लेकिन इन बैठकों में कई नाजुक मुद्दों पर विचार ही नहीं किया गया. इनमें अधिकारियों के इस्तीफे भी शामिल हैं. परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष राजा रमन्ना ने हालांकि साल भर पहले इस्तीफा दे दिया था पर अभी तक उनके स्थान पर किसी की नियुक्ति नहीं हो पाई है. इसी तरह हाल ही में, केंद्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एन.वी.के. मूर्ति, जो 'डिस्कवरी ऑफ इंडिया' परियोजना के निदेशक भी हैं, अपना कायभार केंद्र के वित्त निदेशक एम.के. बहल को सौंप चुके हैं.

केंद्र के संस्थापक और बंबई इंका के पूर्व अध्यक्ष रजनी पटेल के पदच्युत होने और फिर उनका निधन हो जाने के बाद यह केंद्र पूरी तरह सरकारी अनुदान का मोहताज हो गया था. अभी तक इकट्ठा 12 करोड़ रुपए की राशि एक तारामंडल, 930 सीटों के सभागार, डिस्कवरी ऑफ इंडिया हॉल और उसकी गोलाकार मीनार बनाने में ही खर्च हो चुकी है. सरकारी खजाने से मिले छह करोड़ रुपए के अलावा केंद्र सरकार इसे तीन करोड़ रुपए का और अनुदान भी देगी. यह रकम इसे नवंबर 1989 में नेहरू जन्मशती के मौके पर डिस्कवरी ऑफ इंडिया प्रदर्शनी के अंतिम चरण में मिलेगी.

दस एकड़ में फैली इस विशाल परियोजना की अभी तक सचमुच की उपलब्धि 550 सीटों वाले नेहरू तारामंडल का निर्माण है, जहां पिछले ग्यारह वर्षों में करीब पांच लाख दर्शक आ चुके हैं. लेकिन यह भी सच है कि यहां पिछला प्रमुख दृश्य-श्रव्य कार्यक्रम 'सीक्रेट लाइफ ऑफ स्टार्स' मार्च 1987 में ही रिलीज हुआ था. इतने लंबे अरसे तक एक ही कार्यक्रम की पुनरावृति ने इन अफवाहों को ही तूल दिया है कि संस्थान के निदेशक वी.एस. वेंकटवरदन भी

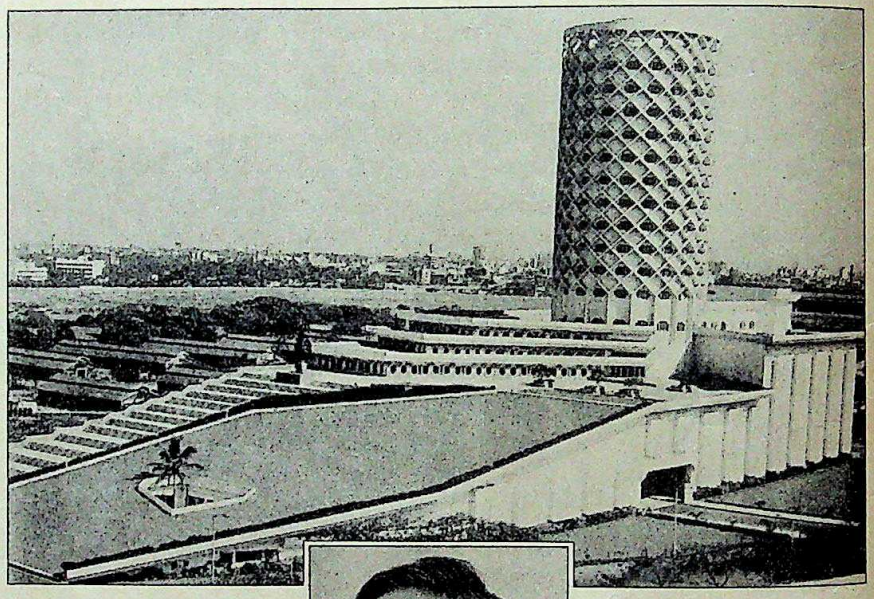

नेहरू केंद्र (ऊपर) और (बाएं) मूर्तिः नाराजगी

केंद्र की समस्याओं से हतोत्साहित हो चले हैं. लेकिन वेंकटवरदन का कहना है कि 'सीक्रेट लाइफ' की लोकप्रियता के कारण ही इसे इतने लंबे अरसे तक दिखाया जाता रहा.

केंद्र की प्रमुख योजना 'डिस्कवरी ऑफ इंडिया हॉल' का इतिहास भी अजीबोगरीब रहा है. हर नया निदेशक योजना के पुराने प्रारूप को रद्द करके नया तैयार करता रहा. सबसे पहले इसे परंपरागत संग्रहालय के रूप में विकसित करने की योजना थी जहां उपमहाद्वीप के प्रागैतिहासिक काल से वर्तमान काल तक का जीवन प्रदर्शित किया जाता. इसके बाद अहमदाबाद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन ने विज्ञान-इतिहासकार बी.वी. सुब्बरैय्या और नर्तकी चंद्रलेखा के सहयोग से इसका नया प्रारूप तैयार किया.

केंद्र की स्थापना के समय से ही इसे इंका का शगूफा माना जाता रहा है जिसका इसे खामियाजा भी भुगतना पड़ा. पटेल के साथ इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय की नाराजगी होते ही इसका निर्माण काफी समय तक ठप रहा. बाद में पटेल जब रमन्ना के पक्ष में पद से हटे तभी काम आगे सरका. पटेल की मृत्यु, अंतुले के निष्कासन और फिर जल्दी-जल्दी बदलते मुख्यमंत्रियों के कारण यह केंद्र लंबे समय तक उपेक्षित रहा. अब राजीव गांधी इसके नए संरक्षक हैं. पर केंद्र का भविष्य पूरी तरह इंका की अंदरूनी राजनीति से ही जुड़ा हुआ है. चव्हाण इसके अध्यक्ष हैं. चव्हाण राजीव की सलाह के बिना तिनका भी नहीं हिलाना चाहते जबकि उनके विरोधी चाहते हैं कि कोई भी निर्णय उनके गुट के विरुद्ध न जाए.

रमन्ना का इस्तीफा कार्यकारिणी के पुनर्गठन की तैयारी माना जा रहा है. पूर्व केंद्रीय गृह सचिव राम प्रधान अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किए जाने से पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद के प्रमुख प्रत्याशी थे. परमाणु ऊर्जा आयोग में रमन्ना के उत्तराधिकारी एस.आर. श्रीनिवासन का नाम भी इस पद के लिए सुझाया जा रहा है.

जब तक कोई कर्मठ, उत्साही महासचिव इस केंद्र में नए प्राण नहीं फूंकता, केंद्र की भारी-भरकम योजना अधर में ही लटकी रहेगी— ठीक उसी तरह जिस तरह पंडित नेहरू का आधुनिक भारत के निर्माण का स्वप्न अधूरा ही रहा.

—एम. रहमान

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उत्तर प्रदेश

नए नाते-रिश्ते

जिलाधीशों के बीच राजीव

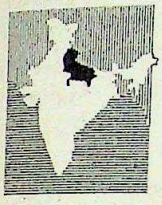

तीन साल पहले प्रधानमंत्री राजीव गांधी का कोई नया कदम बड़ी घटना माना जाता था. लेकिन अब ऐसे कदमों को राजनैतिक चालबाजी कहकर खारिज कर दिया जाता है. पिछले पखवाड़े गोरखपुर में राजीव की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश के जिला मजिस्ट्रेटों की कार्यशाला का मामला भी कुछ ऐसा ही है.

प्रधानमंत्री तथा प्रदेश के 58 जिला मजिस्ट्रेटों में से 55 के बीच 'जवाबदेह प्रशासन' इस विषय पर सीधा संवाद एक अपूर्व घटना थी. विपक्षी दलों ने इसे राज्यों की स्वायत्तता में केंद्र का सीधा हस्तक्षेप माना. राज्य के संसदीय मामलों के मंत्री अम्मार रिजवी ने विधानसभा में एक बयान दिया कि संविधान के अनुच्छेद 256 और 257 के तहत केंद्र को ऐसा करने का संवैधानिक अधिकार है.

सूचना विभाग

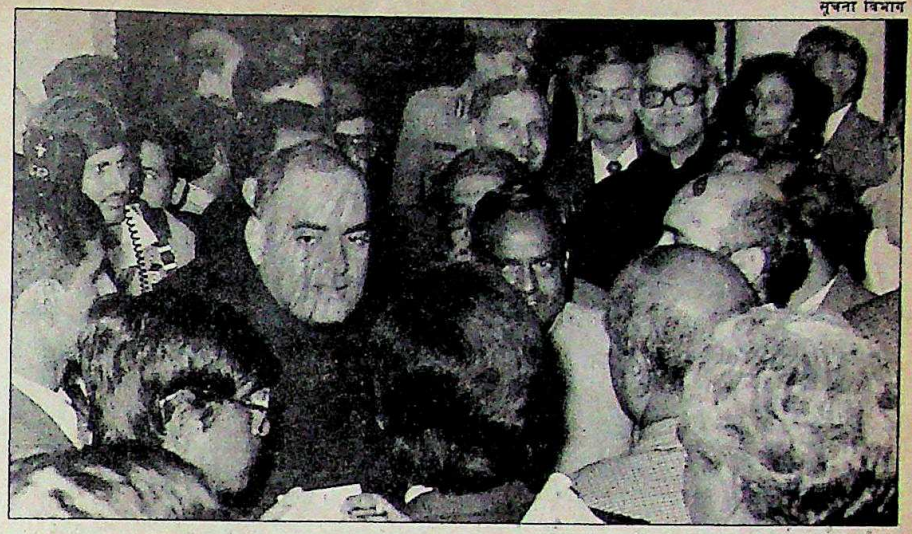

गोरखपुर में राजीव गांधी के साथ बीर बहादुर: एक और राजनैतिक चाल

लेकिन राज्य सरकार ने दूसरे आरोपों पर कुछ नहीं कहा. इनमें से एक मुख्य आरोप है कि कार्यशाला का आयोजन मुख्यमंत्री बीरबहादुर सिंह की राजनैतिक छवि निखारने के लिए किया गया. ऐसे आयोजनों के लिए उपयुक्त जगह लखनऊ के अगले वर्ष से सिलसिला शुरू हो गया. स्थानीय नेताओं ने नेत्रदान करके प्रोत्साहन दिया. इनमें पूर्व मंत्री सीताराम जाजू, राज्य पथ परिवहन निगम के पूर्व अध्यक्ष रघुनंदन लाल वर्मा शामिल हैं.

दवे कहते हैं, "परिवार में कोई मरता है तो अब लोग खुद भी हमारे पास आने लगे हैं." और आसपास के गांवों के लोगों द्वारा भी नेत्रदान असामान्य बात नहीं रह गई है. मसलन नीमच से 20 किमी दूर जीरन से एक बार आधी रात को एक फोन आया और नेत्र बैंक के लिए एक जोड़ी आंखें और मिल गईं.

और ध्यान देने की बात तो यह है कि नीमच में नेत्र प्रत्यारोपण की अच्छी सुविधा है भी नहीं. अधिकांश आंखें या तो 300 किमी दूर इंदौर या फिर राजस्थान के कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर जैसे बड़े शहरों में भेज दी जाती हैं.

लायंस क्लब के सदस्य आम तौर पर लोगों से नेत्रदान फार्म भरवाते हैं ताकि क्लब को मृत्यु के बाद आंखें लेने का अधिकार मिल जाए. दवे कहते हैं, "कोशिश है कि परिवारवालों के पहुंचने से पहले संबंधित परिवार तक पहुंचें."

और दवे हैं कि सुबह-सुबह मंदिर जाने के बजाय हर रोज पूरे भक्तिभाव से स्थानीय अस्पताल जरूर जाते हैं.

—नरेंद्र कुमार सिंह, नीमच में

मध्य प्रदेश

कस्बे की करामात

बारह वर्षीय राहुल चोरडिया पिछले वर्ष चल बसा. बताया जाता है कि उसके गुर्दे ने काम करना बंद कर दिया था. लेकिन मृत्यु से पहले पता नहीं उसके मन में क्या उमड़-घुमड़ रहा था. उसकी मौत इसलिए हुई क्योंकि किसी ने उसे गुर्दा नहीं दिया. लेकिन मरने से पहले वह अपनी आंखें दान कर गया ताकि कोई "इन आंखों से दुनिया देख सके."

पश्चिमी मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के 70 हजार आबादी वाले नीमच कस्बे का यह किशोर महानगर वालों के लिए कुछ सबक तो छोड़ ही गया है. लायंस क्लब की नीमच शाखा की सक्रियता के कारण यह रूढ़िवादी कस्बा शायद देश का एकमात्र कस्बा है जो दृष्टिहीनों के लिए आंखें शहरों को भेज रहा है. पिछले चार वर्षों में यहां 174 जोड़ी आंखें दान की जा चुकी हैं.

नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की मृत्यु के चार घंटे के भीतर आंखें निकाल ली ज़ानी चाहिए. लेकिन अक्सर गमगीन परिवारवाले इसके लिए राजी नहीं होते भले ही मृत व्यक्ति ने नेत्रदान की सहमति दे रखी हो. लायंस क्लब की नीमच शाखा के उपाध्यक्ष और व्यापारी भानु दवे कहते हैं, "कई बार तो परिवार-वाले हमें इस तरह देखते हैं जैसे हमारी हत्या कर देंगे लेकिन कुछ समझदार लोग भी होते हैं."

नेत्रदान अभियान 1983 में जब शुरू किया गया था तो क्लब के सदस्य जहां भी डॉक्टरों के साथ पहुंचते थे, लोग प्रायः उन्हें लौटा देते थे. लेकिन सतत प्रयासों के बाद अब कामयाबी मिल रही है और लोगों का रवैया भी बदल रहा है. क्लब को पहला नेत्रदान 20 अगस्त 1983 को कमला देवी ने किया था. इसके बाद

लायंस क्लब की अपील

भानु दवे

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बदले मुख्यमंत्री के गृहनगर गोरखपुर में यह कार्यशाला रखने से यह आरोप दमदार भी हो जाता है. मुख्यमंत्री के नजदीकी सूत्रों के मुताबिक इस आयोजन का असली मकसद था— विश्वनाथ प्रताप सिंह के 5 जनवरी के कामयाब दौरे को बेअसर करने के लिए इस शहर में राजीव गांधी को लाना. मुख्यमंत्री ने कार्यशाला की कामयाबी में कोई कसर बाकी नहीं रखी. कार्यशाला में मौजूद एक जिला मजिस्ट्रेट ने बताया, "मुख्यमंत्री ने हमारी देखभाल अच्छी तरह की."

प्रधानमंत्री से छोटी-मोटी टोलियों में बातचीत करने का अवसर और खुला वातावरण उनके लिए अहम साबित हुआ. कार्यशाला में जनता की शिकायतों का निबटारा, मानव संसाधनों का विकास, कार्यपद्धतियों को तर्कसंगत बनाना, जिला प्रशासन के उद्देश्यों पर अमल और विकेंद्रीकरण तथा जवाबदेही जैसे संगठनात्मक मामलों वगैरह पर राजीव गांधी ने 10-10 जिला मजिस्ट्रेटों की पांच-पांच टोलियों से अलग-अलग विचार-विमर्श किया. टोलियों में बातचीत करने के सत्र के बाद सभी मजिस्ट्रेटों के साथ आम बैठक भी हुई.

इस बैठक की मुख्य बात विभिन्न मुद्दों पर बातचीत से भी ज्यादा इसके प्रति प्रधानमंत्री का रुख था. कार्यशाला में हिस्सा लेने वाले एक अधिकारी ने कहा, "माहौल गंभीर विचार-विमर्श का नहीं बल्कि अनौपचारिक बातचीत का ही था. हममें से कइयों के लिए तो प्रधानमंत्री के साथ बैठकर बातचीत करने का यह पहला मौका था" इसमें हिस्सा लेने वाले अधिकारियों के अनुसार प्रधानमंत्री बार-बार कह रहे थे कि जिला मजिस्ट्रेटों के पास और अधिकार होने चाहिए. उनके ये विचार कार्यशाला में गए अफसरों के लिए निश्चित रूप से उत्साहवर्धक साबित होंगे. जैसा कि एक अधिकारी ने कहा, "इस रवैये का दोहरा असर होगा. अगर वे हमारा समर्थन करेंगे तो हममें से अधिकांश उनके समर्थन में भी जुटेंगे."

लेकिन कार्यशाला में भाग लेने वाले अफसरों से भी ज्यादा संतुष्ट मुख्यमंत्री ही दिखते हैं क्योंकि उन्हें राजीव गांधी के साथ अकेले में कुछ घंटे बिताने का मौका मिला. वे कहते फिरे कि "प्रधानमंत्री बहुत खुश हैं." इस कार्यशाला से जिला मजिस्ट्रेटों को ज्यादा अधिकार देने दिशा में कुछ प्रगति हुई हो या नहीं, इतना तय है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को इस प्रयोग को पूरी तरह से कामयाब कहने का मौका जरूर मिल गया. उन्होंने सही लोगों को अपनी तरफ कर लिया है.

—विलीप अवस्थी

हिमाचल प्रदेश

गैरजरूरी कानून

विपक्ष को मौका मिला

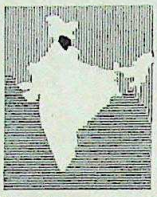

यह कदम बेमिसाल था और गैरजरूरी भी. हिमाचल प्रदेश में सत्तारूढ इंका ने पिछले साल के अंत में एक विधेयक पारित करवा लिया जिसके तहत राज्य सरकार कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को कुछ न्यायिक अधिकार प्रदान कर सकती है. दंड प्रक्रिया संहिता (हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 1987) को अभी राष्ट्रपति की मंजूरी मिलनी बाकी है.

यदि यह मंजूरी मिल गई तो हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य होगा जहां सरकार न्यायपालिका के अधिकारों का अतिक्रमण करेगी. आश्चर्य नहीं कि यह विधेयक खासे विवाद का मुद्दा बन गया है. इससे वीरभद्र सिंह सरकार काफी परेशानी में पड़ गई है.

मौजूदा कानून में संशोधन के लिए सरकार की मुख्य दलील यह है कि वह छोटे-मोटे फौजदारी मामलों को जल्दी निबटाना चाहती है. पर इस विधेयक का प्रभाव भारतीय दंड संहिता की 60 धाराओं पर पड़ेगा. यह विधेयक कानून बन गया तो इन अधिनियमों के तहत आने वाले अपराधियों के मुकदमों की सुनवाई नौकरशाही भी कर सकेगी.

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह कहते हैं, "यह विधेयक जब दिसंबर के शुरू में पेश किया गया था तो किसी ने भी आपत्ति नहीं उठाई थी. लगता है विपक्ष के पास और कोई मुद्दा नहीं बचा है." सबसे पहले इसकी आलोचना भाजपा नेता जगदेव चंद्र ने की. उन्होंने विधेयक की धाराओं को 'तानाशाही' बताया. जनमोर्चे के नेता मेजर विजय सिंह मनकोटिया भी इसके खिलाफ बोले. विधानसभा में जब यह विधेयक रखा गया था तब तो विपक्ष ने इसे नजरअंदाज किया था पर 30 दिसंबर को इसके पारित होने के बाद विपक्ष ने जोर-शोर से इसका विरोध करना शुरू कर दिया.

कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को न्यायिक अधिकार प्रदान करने वाले विधेयक को मंजूर करवाकर राज्य सरकार ने विपक्ष के हाथ में एक अच्छा मुद्दा थमा दिया है

भवान सिंह

वीरभद्र सिंह

विपक्षी पार्टियों और कुछ सियासी हस्तियों के गठबंधन—हिमाचल क्रांतिकारी मोर्चा—ने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन में अनुरोध किया है कि विधेयक को मंजूरी न दी जाए. इस पर हस्ताक्षर करने वालों में पूर्व मुख्यमंत्री रामलाल, राज्य जनता पार्टी की अध्यक्ष श्यामा शर्मा, लोकदल (ब) के नेता नरेंद्र ठाकुर, लोकदल (अ) के डी.आर. दुग्गल, माकपा के कमलेश्वर पंडित और कांग्रेस (स) के एम.एन. शुक्ल हैं.

विपक्ष द्वारा उठाया गया सबसे अहम मुद्दा यह है कि चूंकि हिमाचल प्रदेश एक शांत राज्य है जहां अपराध दर वास्तव में घट रही है, इसलिए वहां इस विधेयक का कोई औचित्य नहीं है. सरकार इसका प्रयोग राजनैतिक विरोधियों के खिलाफ ही करेगी. गृह मंत्रालय भी देख रहे मुख्यमंत्री के पास इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं है.

विपक्ष ने सरकार की इस दलील का भी खंडन किया है कि विधेयक से न्यायपालिका का बोझ भी घटेगा. मनकोटिया कहते हैं, "उच्च न्यायिक सेवाओं की भरती 1984 से बंद है और कई जगहें खाली पड़ी हैं. सरकार को यह काला कानून लाने के बजाय न्यायिक सेवा मजबूत बनानी चाहिए थी."

अब वीरभद्र बचाव को मजबूर हो गए हैं, "हमने यह विधेयक अभी राष्ट्रपति को भेजा भी नहीं है. यदि विपक्ष ने सदन में इस पर बहस की होती तो हम इसे पुनर्विचार के लिए चयन समिति को भेज सकते थे. हमने अभी भी दरवाजे बंद नहीं किए हैं और इसे केंद्र को भेजने की जल्दी नहीं कर रहे." संभव है, सरकार इस मामले में पीछे हटे. पर जो नुकसान होना था, हो चुका है. विपक्ष के पास वीरभद्र सरकार के खिलाफ एक अहम मुद्दा हाथ लग गया है.

—पंकज पचौरी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

है कोई छुट्टा देने वाला?

पार्किंग में खड़ी गाड़ियों की भीड़ से अपनी कार निकालने से पहले ही मैंने वहां तैनात चौकीदार को दो रुपए का नोट देते हुए कहा, "लो भइया, एक रुपया वापस कर देना!"

वह बोला, "साहब, एक का नोट तो छुट्टा नहीं है अपने पास."

"तो फिर किसी और से उधार लेकर मुझे दे दो," मैंने कहा.

"अरे साहब, एक का नोट और इन दिनों?" वह बोला, "इतना खुशनसीब कौन है आजकल?"

मैंने दांत भींच लिए. उससे नोट वापस लेकर मैं बोला, "ठीक है, ठीक है, मैं ही नोट तुड़वा लूंगा." मैंने आसपास के सभी दुकानदारों और वहां खड़े सज्जनों से दो रुपए के खुले मांगे पर किसी के पास भी एक रुपए के नोट नहीं थे. अचानक मुझे सूझा कि चलो अपने बैंक चलते हैं. 100 रुपए का चेक काटकर मैंने कैशियर को थमाया और उससे मिन्नत की कि भइया एक-एक के नोटों की गड्डी देना

"सॉरी, भाई साहब," कैशियर बोला. "हमारे पास तो एक-एक के नोटों का स्टॉक नहीं रहा."

मुझे गुस्सा आ गया, "अरे! तुम्हारा बैंक है या क्या है. देखो, एक-एक के नोट किसी खाने में पड़े मिल जाएंगे. बैंक में तो होने ही चाहिए."

वह हिचकिचाया और बोला, "देखिए साहब, बेहतर है इस बारे में आप मैनेजर से बात कर लें."

मैंने मैनेजर से जाकर फरियाद की तो वह सिर थामकर बोला, "सर, इन दिनों एक-एक के नोटों की बहुत ही किल्लत है. उसके लिए भारी रसूख भिड़ाने की जरूरत है. अगर आप मुझे कोई तगड़ी सिफारिश ला दें तो मुमकिन है रिजर्व बैंक में काम कर रहा मेरा एक दोस्त आपकी मदद कर सके और आपको एक-एक के नोटों की गड्डी दिलवा दे."

मैं नारायण दत्त तिवारी के पास पहुंचा और उन्हें अपनी व्यथा सुनाई. मेरी गुजारिश थी, "आप वित्तमंत्री हैं. अगर अपना प्रभाव इस्तेमाल करें तो मुझे यकीन है कि आप मुझे एक-एक के नोटों की गड्डी दिलवा सकते हैं."

तिवारी खीझ गए और बोले, "अरे भई, आप किस दुनिया में जी रहे हैं? मेरा कोई असर-वसर नहीं है. अच्छा होता आप गोपी अरोड़ा के पास जाते. उनकी ही चलती है."

"यह क्या कह रहे हैं? आप तो कैबिनेट मंत्री हैं और अरोड़ा महज एक सचिव. उनकी कैसे चल सकती है?"

तिवारी उदास-से हो गए. बोले, "ऐसा ही होता है यहां. अरोड़ा तमाम वक्त प्रधानमंत्री के यहां काटते हैं और

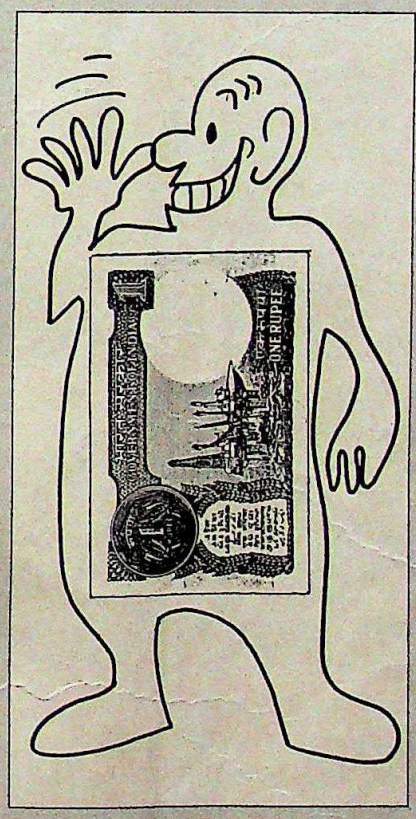

मेरी राजीव जी तक मुश्किल से पहुंच हो पाती है. इसलिए मेरा असर भी नहीं है."

मैं उठकर गोपी अरोड़ा के पास चल दिया. उन्होंने मेरी बात सुनी और बनावटी हंसी हंसकर बोले, "क्यों बना रहे हैं आप! प्रधानमंत्री के साथ मैं उठता-बैठता जरूर हूं पर उनसे दून स्कूल की पुरानी यादें ताजा नहीं कर पाता. इसलिए मेरा बीच में पड़ना बेकार है, असल में मेरा असर है ही नहीं. आप सुमन दुबे को क्यों नहीं पटाते?"

मैंने उन्हें नमस्ते की और सुमन दुबे से मिलने जा पहुंचा, "सुमन, मुझे पता चला है कि तुम राजीव गांधी के बहुत करीब हो और उनसे दून स्कूल की पुरानी यादें ताजा करते रहते हो. मेहरबानी करके तुम अपना प्रभाव इस्तेमाल कर मुझे एक-एक रुपए के नोटों की गड्डी दिलाने में मदद कर सकते हो?"

"प्रधानमंत्री इन दिनों दून स्कूल की कोई परवाह नहीं करते," सुमन कुछ तल्खी से बोले, "अब उन्होंने नए दोस्त बना लिए हैं जिनके साथ वे लक्षद्वीप की सैर पर जाते हैं. बेहतर है आप अमिताभ से बात करें. वही कुछ कर सकते हैं."

मैंने अमिताभ के यहां जाकर गुहार लगाई. "भई, मैं तो अब संसद सदस्य भी नहीं हूं," अमिताभ दुखी होकर बोले, "हालात बदल गए हैं. अब तो मैं सोनिया जी की सलाह के बिना कुछ नहीं करता. अच्छा हो, आप उनसे जाकर कहें."

सोनिया गांधी ने बड़े गौर से मुझे सुना. फिर सिर हिलाकर सखेद बोलीं, "छह साल पहले या पांच साल पहले तक भी मैं आपके लिए कुछ कर सकती थी. पर अब मैं पूरी तरह भारतीय पत्नी बन चुकी हूं. मैं तो अपने देवता राजीव के हुक्म की ही तामील करती हूं. आप उन्हीं से गुजारिश करें."

आखिर मैं राजीव गांधी के दरबार में पहुंचा. उनके आगे समस्या रखते हुए मैंने विनती की, "हे प्रधानमंत्रीवर, आप अपना प्रभाव इस्तेमाल करें तो यकीनन मुझे एक-एक रुपए के नोटों की गड्डी दिलवा सकते हैं."

"क्या कहा?" राजीव भड़क उठे. "तुम मुझे प्रभाव इस्तेमाल करने को कहते हो? चाहते हो मैं तरफदारी करूं? मुझे रिश्वतखोर बनाने पर तुले हो? फौरन मेरे दफ्तर से बाहर हो जाओ."

निराश मैं कार पार्किंग के चौकीदार के पास लौटा. दो रुपए का नोट उसे देकर बोला, "बाकी भी तुम रख लेना. मुझे तो एक रुपए का नोट नहीं मिला."

"साहब मैंने पहले ही बता दिया था," चौकीदार की बांछें खिल उठीं.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आंध्र प्रदेश

अदला-बदली

रामराव की मुश्किल बढ़ी

आंध्र प्रदेश के मतदाताओं ने नेताओं को ही चक्कर में डाल दिया. पिछले पखवाड़े हुए दो विधानसभाई चुनावों में मतगणना जब पूरी हुई तो तेलुगु देशम और विपक्षी इंका ने पाया कि उन्होंने महज सीटों की अदला-बदली ही की है. इंका ने जहां श्रीकलाहस्ती सीट तेलुगु देशम से छीनी, वहीं इंका के कब्जे में अब तक रही वायलापाडु सीट तेलुगु देशम ने हथिया ली.

इन परिणामों से तेलुगु देशम सरकार को दुखदायी सबक यह मिला कि उसकी तुष्टीकरण की नीति सफल नहीं हो सकती है. पिछले महीने मुख्यमंत्री नंदमूरि तारक रामराव के खिलाफ हाई-कोर्ट के जल्दबाजी में दिए फैसले के तुरंत बाद सरकार ने अनेक रियायतों की घोषणा की थी (देखें इंडिया टुडे, 31 जनवरी).

एकमुश्त रियायतों और राहत कार्यक्रमों का मकसद उन वर्गों का समर्थन जीतना था जो सरकार की नीतियों से नाराज हो गए थे. इनके तहत जिन वर्गों को फायदा मिला उनमें सरकारी कर्मचारी, कपड़ा व्यापारी, अल्पसंख्यक और परिवहन कर्मचारी शामिल हैं. एकमुश्त रियायतें इस प्रकार हैं:

- सरकारी कर्मचारियों के लिए 10,000 घरों का निर्माण करना; किसी एक स्थान पर सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की अवधि दो से बढ़ाकर तीन साल करना.
- वाहनचालकों और क्लीनरों के बच्चों के लिए एक विशेष कल्याण कोष बनाना.
- एक करोड़ रुपए की लागत से 230,000 रिक्शा चालकों को दो-दो जोड़ी कपड़े देना.
- अल्पसंख्यकों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों और कॉलेजों को प्रबंधन की ज्यादा आजादी देना.
- उर्दू माध्यम से शिक्षा देने वाले तीन आवासीय और 100 प्राथमिक स्कूल स्थापित करना जो 1988-89 से शुरू होंगे.
- राज्य में आने वाले कपड़े पर प्रवेश कर दो से घटाकर एक प्रतिशत करना.
- दो लाख से कम का सालाना कारोबार करने वाली दुकानों को सतर्कता विभाग और पुलिस के निरीक्षण से मुक्त रखना.

लेकिन इंका ने हाईकोर्ट के इस फैसले को ही चुनाव प्रचार का मुख्य मुद्दा बनाया कि रामराव सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग किया है. केंद्रीय उद्योगमंत्री और आंध्र प्रदेश इंका के अध्यक्ष जे. वेंगलराव तथा केंद्रीय गृह राज्यमंत्री पी. चिदंबरम ने अपने प्रचार अभियान में तेलुगु देशम अध्यक्ष पर 'तेलुगु जनता के स्वाभिमान' को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया.

रामरावः मुश्किलें और भी हैं

बाबजी/जनता स्टुडियो

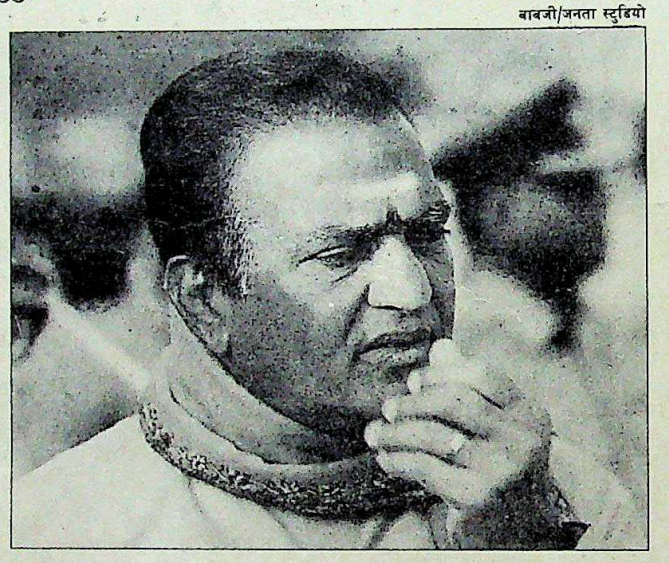

इन उपचुनावों से तेलुगु देशम को यह सबक मिला कि उसकी तुष्टीकरण की नीति सफल नहीं हो सकती है

पर मतदाता आरोपों और प्रत्यारोपों की रौ में नहीं बहे. उनके लिए स्थानीय और तात्कालिक मुद्दे ही महत्वपूर्ण थे. वायलापाडु में अल्पसंख्यकों से मतदान से पहले किए गए वायदों (इस चुनाव क्षेत्र में 18,000 मुस्लिम मतदाता हैं) और प्राथमिक चिकित्सा केंद्र और मंडल कार्यालय खोलने के आश्वासनों ने तेलुगु देशम का पलड़ा इंका से कुछ कदर भारी कर दिया. इंका ने यहां अमरनाथ रेड्डी की विधवा को मैदान में उतारा. रेड्डी ही पहले खुद इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे. पर प्रतिनिधि के निधन के बाद उनकी विधवा को जिताने की भारतीय चुनावी परंपरा को तोड़ते हुए मतदाताओं ने तेलुगु देशम के 26 वर्षीय सी. रामचंद्र रेड्डी को चुन लिया. उन्होंने एन. सरोजम्मा के विरुद्ध 3,200 वोटों के मामूली अंतर से विजय हासिल की.

मगर पार्टी को श्रीकलाहस्ती में विजय से राहत मिली. यहां उसके प्रत्याशी चेनचू रेड्डी ने तेलुगु देशम के के. श्रीराममूर्ति को 4,419 मतों के अंतर से पछाड़ दिया.

इन उपचुनावों में तेलुगु देशम के प्रचार अभियान की कमान रामराव के विवादास्पद दामाद एन. चंद्रबाबू नायडू ने संभाली. वे 12 दिनों तक इस क्षेत्र में बने रहे. दोनों हलके उनके जिले चित्तूर में आते हैं.

एक-एक विधानसभा सीट जीतकर इंका और तेलुगु देशम मतदाताओं के रुझान को अपने-अपने पक्ष में आंक रही हैं. पर कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि दूसरे पक्ष ने लोकप्रियता खो दी है.

वायलापाडु में स्थानीय मतदाताओं ने तेलुगु देशम के श्रममंत्री पी. शिव रेड्डी का जो अपमान किया उससे पार्टी को ठेस ही पहुंची. शिव रेड्डी के समर्थकों ने पालेम गांव के मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर जाने से रोका था. इस पर ग्रामीणों ने उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. जब ग्रामीणों ने उन्हें छोड़ने से मना कर दिया तो रेड्डी ने धमकी दी कि वे उन्हें 'सबक सिखाने के लिए' अपने गिरोह को लेकर एक घंटे में लौट रहे हैं. लेकिन अब सबक सीखने की बारी रेड्डी की थी. पालेम के लोगों ने मंत्री और उनके समर्थकों का घेराव कर उन्हें पीटना शुरू कर दिया. इस बार रेड्डी ने गोली चला दी. हालांकि पुरुष वहां से हट गए पर महिलाओं ने उन पर पिसी मिर्चें फेंकी और उनके कपड़े फाड़ दिए. आखिर मंत्री और उनके सुरक्षा कर्मचारियों को सिर पर पांव रखकर गांव से भागना पड़ा.

रामराव के लिए शिव रेड्डी प्रकरण और चुनाव परिणाम बड़े बुरे वक्त में सामने आए हैं. हाईकोर्ट में अपने विरुद्ध चल रहे मुकदमे की कार्रवाई रुकवाने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अवकाश याचिका दायर कर रखी है. अदालत चाहे जो भी फैसला करे, तेलुगु देशम के सामने इस समय सबसे बड़ा काम तो अपनी धुंधली छवि को निखारने का है.

—अमरनाथ के. मेनन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

टाइम्स ऑफ इंडिया

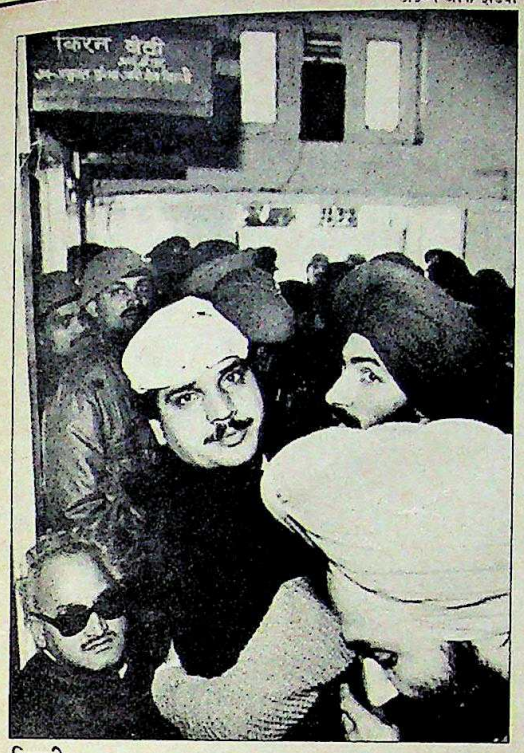

दिल्ली

बात का बतंगड़

असली मुद्दा भुला दिया गया

दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज में चोरी की कथित घटना से इस गड़बड़झाले की शुरुआत हुई. इसके तुरंत बाद एक वकील को हथकड़ी लगाए जाने के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया और एक हफ्ते के अंदर ही दिल्ली की पुलिस उपायुक्त किरण बेदी के दफ्तर के बाहर पुलिसिया डंडों से 18 प्रदर्शनकारी वकीलों के घायल होने के बाद राजधानी के वकीलों ने उनके खिलाफ बाकायदा जंग का ऐलान कर दिया.

इस लड़ाई में दोनों ही पक्ष एक-दूसरे पर अनुचित बरताव का इल्जाम लगा रहे हैं. बेदी का कहना है कि गाली-गलौज करते सैकड़ों वकीलों ने पुलिस को उन्हें पीटने पर 'वाकई मजबूर' कर दिया जबकि वकीलों का कहना है कि असल में एक वकील पर चोरी का इल्जाम लगाते हुए अखबारों में एक दिन पहले छपे बेदी के बयान से ही वे भड़क उठे.

16 जनवरी को एक वकील राजेश अग्निहोत्री (26) को जब हथकड़ी पहनाकर अदालत लाया गया तो वकीलों के गुस्से का पारावार न रहा और उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया क्योंकि कानूनन खतरनाक अपराधियों और जिन पर फरार होने का

वकीलों को बेदी के दफ्तर में घुसने से रोकती पुलिस

अंदेशा हो ऐसे अपरोपियों को ही हथकड़ी लगाई जा सकती है. पुलिस ने उन पर सेंट स्टीफंस कॉलेज के लेडीज कॉमन रूम से एक ऑडियो कैसेट और 101 रुपए चुराने का इल्जाम मढ़ा था.

लेकिन इस झगड़े में असली घटना को एकदम भुला ही दिया गया. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एम.सी. भंडारे कहते हैं, "यह बार एसोसिएशन और किरण बेदी के बीच की लड़ाई बन गई है." दिल्ली के पुलिस आयुक्त वेद मारवाह कहते हैं, "मुझे इस घटना से काफी अफसोस हुआ. न्याय व्यवस्था के दो प्रमुख अंगों को आपस में लड़ता देख लोग क्या सोचेंगे?"

उनका कहना है, "हथकड़ी लगाए जाने का अभी तक किसी ने समर्थन नहीं किया है. लेकिन अगर शिकायतें जायज हैं तो उनके निबटारे का रास्ता भी है. पर वे तो राजनैतिक आंदोलनकारियों की तरह बरताव कर रहे थे."

भंडारे का कहना है कि हड़ताल से वकील समुदाय भी उतना ही दुखी है. लेकिन अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने का यही एक रास्ता बच गया है. बहरहाल इस कटुता और गुस्से में किसी की बात सुनने से ज्यादा अपनी-अपनी बात सुनाने का ही माहौल बना हुआ है.

—डेविड देवदास

केरल

वामपंथी घाटे में

इंका ने अब कमर कसी

सपना पूरा नहीं हो पाया. केरल की 10 महीने पुरानी ई.के. नयनार सरकार हालांकि अपनी भारी कामयाबी निश्चित मान रही थी पर पिछले पखवाड़े राज्य में स्थानीय निकायों के चुनाव में सत्तारूढ़ वामपंथी लोकतांत्रिक मोर्चा जरा-भर बहुमत ही हासिल कर सका.

वाम मोर्चा 999 पंचायतों में से 469 पर ही काबिज हो सका, जबकि इंका की अगुआई वाले लोकतांत्रिक मोर्चे ने 455 पंचायतों में जीत दर्ज की. स्थानीय चुनावों के दंगल में पहली बार उतरी भाजपा की झोली में तीन पंचायतें ही पड़ीं. बाकी जगहों पर दोनों मोर्चों की स्थिति बराबर रही. वाम मोर्चे के लिए इससे भी ज्यादा सदमे वाली बात यह रही कि वह 15 नगरपालिकाओं में ही जीत पाया जबकि लोकतांत्रिक मोर्चे ने 25 नगरपालिकाओं पर आधिपत्य जमा लिया. तीन नगरपालिकाओं में दोनों पक्ष बराबरी पर रहे.

कई बातें वाम मोर्चे के खिलाफ गईं. पिछले साल कारोबार पर लगाए गए करों से व्यापारियों को भारी नुकसान पहुंचा था. शहरी इलाकों में ऐसे मतदाता खासी तादाद में हैं. मार्क्सवादियों ने पिछले साल विधानसभा चुनावों के दौरान 10 लाख युवकों को रोजगार देने का वायदा भी किया था. यह वादा भी

नयनार: वोट डालने का इंतजार

खोखला ही साबित हुआ.

वाम मोर्चे के कमजोर प्रदर्शन का असर जिला परिषद प्रशासन विधेयक पर भी पड़ सकता है जिसमें नागरिक निकायों को ज्यादा अधिकार देकर विकेंद्रीकरण पर जोर दिया गया है.

इन चुनावों ने वाम मोर्चे की भीतरी लड़ाई को भी उजागर किया है. उसके कई विद्रोही उम्मीदवारों ने तो नाम तक वापस लेने से इनकार कर दिया. दूसरी ओर राज्य इंका अध्यक्ष ए.के. एंथनी और पूर्व मुख्यमंत्री करुणाकरन में अब पटने से पार्टी को भारी लाभ मिला. एंथनी कहते हैं, "चुनाव नतीजों से पता चलता है कि लोग धीरे-धीरे सरकार से निराश होते जा रहे हैं. वाम मोर्चे के लिए यह अच्छा झटका है." इस बात से वाम मोर्चे के नेता भी शायद ही इनकार कर सकें. —श्रीधर पिल्लै

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रशांत पंजियार

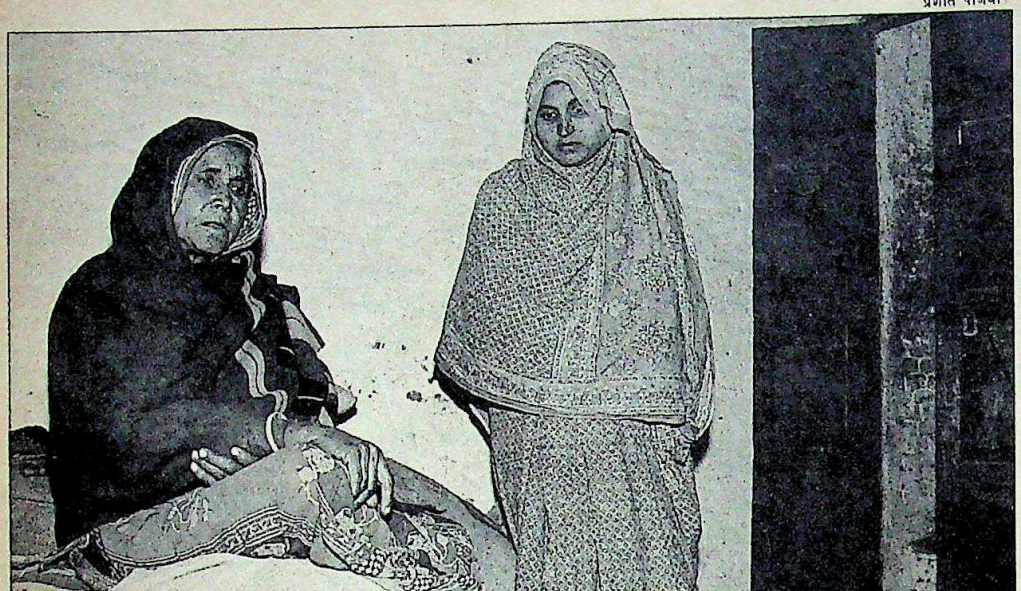

माया त्यागी अपनी सास के साथः पुलिस की दहशत

माया त्यागी कांड

वर्दीवालों पर वज्रपात

सात साल के बाद छह को फांसी और चार को उम्रकैद का फैसला

पिछले पखवाड़े की एक दोपहर बुलंदशहर जिला अदालत में एक फैसला सुनने के लिए 2500 से ज्यादा लोग आ जुटे थे. जब फैसला सुनाया गया तो वहां कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात 200 पुलिसवालों की रूह कांप गई.

अतिरिक्त सेशन जज वी.डी. दुबे ने उत्तर प्रदेश पुलिस के छह कर्मचारियों को फांसी और चार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. आजादी के बाद खाकी वर्दीवालों के खिलाफ इसे सबसे कठोर सजा माना जा रहा है. निलंबित सब-इंस्पेक्टर शिव कुमार गुप्त और जमादार सिंह, हवलदार काशीराम और सिपाही राकेश (बैच नं. 888), आनंद गिरि और राकेश (नं. 720) जब आधे घंटे बाद अदालत पहुंचे तो उन्हें बेड़ियां पहना दी गईं. अब वे सब-इंस्पेक्टर राम गिरि और सिपाहियों—प्रताप सिंह, संता सिंह और सुभाष—के साथ जेल में बंद हैं.

साढ़े सात साल पहले इन लोगों की करतूत से देश थर्रा उठा था. तब ये लोग मेरठ जिले के बागपत थाने में तैनात थे. इन लोगों पर थाने के करीब ही ईश्वर सिंह त्यागी, सुरेंद्र सिंह और राजेंद्र गौड़ को अपने पुलिसिया हथियारों से दिनदहाड़े भून देने का आरोप लगाया गया था.

गोलीबारी के बाद त्यागी की गर्भवती पत्नी माया को, जिसका पांचवां महीना चल रहा था, इन लोगों ने बागपत बाजार में नंगा करके घुमाया और थाने में ले जाकर अपमानित किया. जाट-बहुल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस कांड को लेकर जो गुस्सा भड़का उससे इंदिरा गांधी सरकार भी दहल गई. इस आंदोलन को चलाने वालों में लोकदल के अन्य नेताओं के साथ चरण सिंह और राजनारायण भी थे.

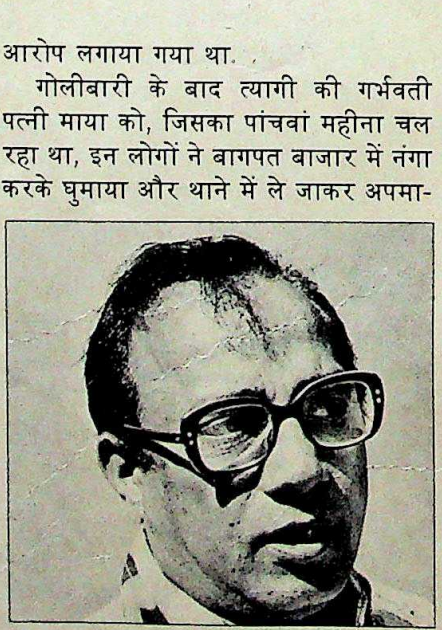

अतिरिक्त सेशन जज दुबेः महत्वपूर्ण फैसला

घटना के कुछ चश्मदीद लोगों ने संवाददाताओं को बताया कि एक पुलिसवाला माया त्यागी से छेड़छाड़ कर रहा था. इस पर माया ने पति और उसके दो साथियों को आवाज देकर बुलाया. ये लोग आकर पुलिसवाले से कहा-सुनी करने लगे तो उसने नजदीक के थाने से और सिपाहियों को बुला लिया. और फिर हिंसक पागलपन का दौर शुरू हो गया. बाद में पुलिसवालों ने आरोप लगाया कि त्यागी के पास बंदूक थी और तीनों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है.

इसके बाद वरिष्ठ सरकारी अधिकारी पी.एन. राय ने घटना की अदालती जांच की. उसमें भी उन्होंने पुलिसवालों को दोषी पाया था. और मुकदमा चलने तक उनके तबादले का सुझाव दिया. हालांकि राय ने पुलिसवालों को बलात्कार के आरोप से बरी कर दिया था. उनका मानना था कि मौका-ए-वारदात पर इकट्ठी विशाल भीड़ के सामने वैसा कर पाना संभव नहीं था.

सारे सबूतों और गवाहियों के परीक्षण के बाद न्यायाधीश ने माना, "यह सब कुछ मुझे आदिमकालीन 'पुलिस राज' की तरह लगता है जहां हर आदमी का जीवन निरंकुश शासक की मर्जी पर निर्भर था."

फैसले में कहा गया है कि 'हत्या' और उसके बाद जो 'वहशियाना हरकत' की गई वह उन 'भूखे भेड़ियों' की करतूत है जो अपने को 'लोगों के जान-माल का रक्षक बताते हैं.' समाज को बचाए रखने के लिए जरूरी है कि ऐसी आसुरी प्रवृत्तियों का सफाया किया जाए. "ताकि समाज में विश्वास कायम हो सके और पुलिस बल पर भी निवारक असर पड़े."

इस तरह अपनी राइफलों का इस्तेमाल करने वाले 6 पुलिसवालों को मौत की सजा सुनाई गई और दूसरे चार पुलिसवालों को हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने का दोषी पाया गया. इस फैसले में भारतीय दंड संहिता की जिन धाराओं के तहत इन लोगों को दोषी पाया गया वे हैं: तीन लोगों की हत्या के लिए धारा 302, अपराध में सहभागिता के लिए धारा 149, हिंसक फसाद के लिए धारा 148, दंगा-फसाद करने के लिए धारा 147

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पुलिस रजिस्टर से सबूत हटाने और झूठे सबूत गढ़ने के लिए धारा 201, सरकारी कर्मचारी होकर झूठे रिकार्ड दर्ज करने के लिए धारा 218, गंभीर रूप से घायल करने के लिए धारा 323, महिला को अपमानित करने के लिए की गई आपराधिक हरकतों के लिए धारा 354 और इन सभी अपराधों की साजिश रचने के लिए धारा 120(बी).

लेकिन अपराधों की भरमार वाले देश के इस इलाके की 'नृशंस और अमानवीय' बन गई पुलिस पर इस फैसले का कोई असर नहीं दिखता. फैसले के दिन स्थानीय पुलिस बागी मूड में थी. उस दिन अदालत में अपने चेहरे ढंक कर आए दस पुलिसवालों की तस्वीरें लेने की इजाजत फोटोग्राफरों को नहीं दी गई.

इस मामले की सुनवाई के दौरान अधिकारियों के रवैये पर भी कई भौंहें तिरछी हुईं. गृह मंत्रालय ने सीआइडी को बागपत के इंस्पेक्टर डी.पी. गौड़ पर मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी. बाद में गौड़ ने अपने खिलाफ अदालती कार्रवाई रोकने के लिए हाईकोर्ट से स्थगन आदेश ले लिया. तत्कालीन मंडल अधिकारी तथा डीएसपी पी.एस. नेगी अदालत में अपने बयान से मुकर गए. उन्हें बागी गवाह घोषित कर दिया गया. इस मामले के प्रमुख सबूत पुलिस के रजिस्टरों का चार साल तक पता नहीं चला. बाद में मुकदमा चलाने वाले सीआइडी अधिकारी एस.बी. शर्मा ने उन्हें ढूंढ़ निकाला.

समय-समय पर फर्जी मुठभेड़ की कहानियों से पश्चिम उत्तर प्रदेश की पुलिस की बदनामी ने अब कहावतों का रूप ले लिया है. इन सबके मद्देनजर न्यायाधीश ने कुछ विशिष्ट सावधानियां भी बरतीं. फैसला सुनाए जाने के दो दिन पहले उन्होंने सभी दस आरोपियों को गिरफ्तार कर लेने का आदेश दिया. सरकार ने न्यायाधीश को सादी वर्दी में एक सशस्त्र सुरक्षा गार्ड भी मुहैया कराया. फैसला लिखे जाने के दौरान चार दिनों तक उनके टाइपिस्ट को उनके घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी.

यहां तक कि फैसले के बाद सजा पाए पुलिसवालों को बेड़ियां न पहनाने के लिए पुलिस ने बुलंदशहर के जेल अधिकारियों पर दबाव भी डाला. हालांकि जेल मैनुअल में मौत की सजा पाए सभी मुजरिमों को बेड़ियां पहनाने के साफ-साफ निर्देश हैं.

इस मामले का सबसे दुखद पहलू तो यह है कि सजा पाए पुलिसवालों को अपने जुर्म का कोई मलाल नहीं है. फैसले के बाद उन्होंने एक स्वर से कहा, "हम दोषी नहीं हैं. न्यायाधीश ने सबूतों की अनदेखी की है. यह फैसला हाईकोर्ट में टिक नहीं पाएगा." गुप्ता ने कहा, "कोई अपराध हुआ यह साफ-साफ प्रमाणित नहीं किया गया है." राकेश ने कहा, "उनका (ईश्वर त्यागी और दूसरों) इस जेल में रिकार्ड है." राम गिरि ने कहा, "न्यायाधीश ने इस तथ्य को नजरंदाज कर दिया कि वे डकैत थे." खुशी राम ने कहा, "अब कौन पुलिसवाला अपराधियों को हाथ लगाएगा?"

संकालसेठी (बागपत में माया त्यागी का मायका) और तिलहेटा (गाजियाबाद में उसकी ससुराल) में लोग एकदम अलग ही मूड में थे. उनके परिवार के सदस्यों ने पुलिसिया आतंक के साये में जीवन निभाना सीख लिया है. उन्हें गांववालों ने फैसले की

अतिरिक्त सेशन जज वी.डी. दुबे के अनुसार यह सब कुछ आदिमयुगीन पुलिस राज की तरह था जहां हर आदमी का जीवन निरंकुश शासक की मर्जी पर हुआ करता था

खबर दी. त्यागी की माता शांति ने कहा, "इससे मेरा बेटा तो मुझे वापस नहीं मिल सकता. लेकिन अब मुझे संतोष है कि उन्हें (पुलिसवालों को) अपने किए का भरना पड़ेगा." इस भयावह घटना का जिक्र ही माया त्यागी को रुला देता है. वह कहती है, "उन्होंने जो कुछ किया अगर उसकी सजा

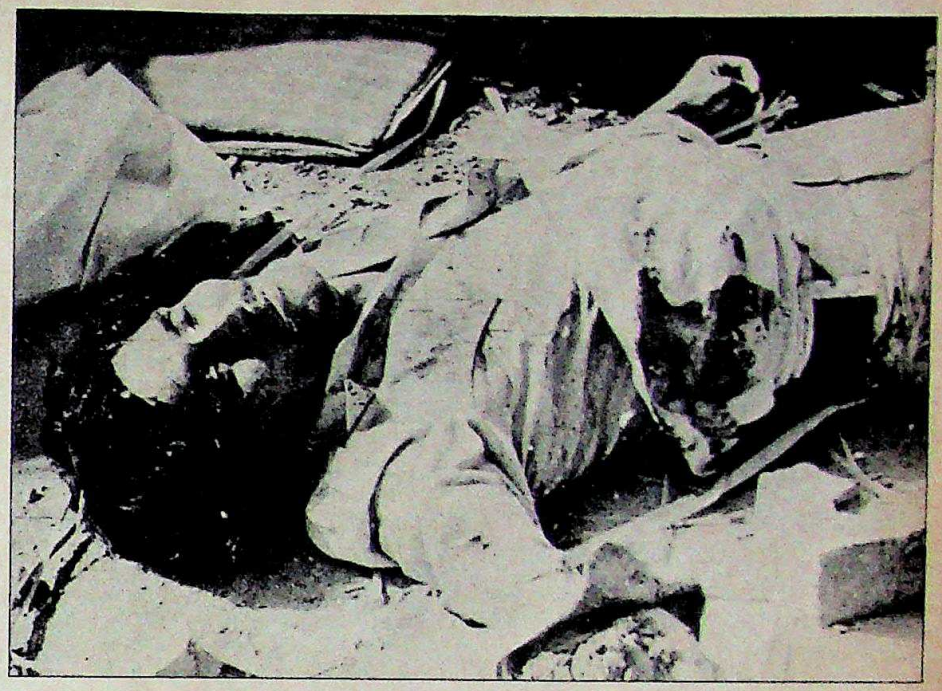

ईश्वर त्यागी: पुलिसिया हथियारों से हत्या

उन्हें नहीं मिलती तो इसका मतलब यही होगा कि सड़क पर कोई भी सुरक्षित नहीं है. लेकिन अब, ऐसा करने के पहले हर कोई दुबारा सोचेगा."

त्यागी परिवार हार चुका है. माया के 7 वर्षीय बेटे दीपक को पुलिस के डर से दूसरे संबंधियों के पास भेज दिया गया है. इस मामले से जुड़े एक सिपाही की हत्या के मामले में जब परिवार के बड़े बेटे विनोद के खिलाफ झूठा मामला बनाया गया तो वह पुश्तैनी खेतीबाड़ी छोड़कर गांव से चला गया. दो और बेटों ने भी दूसरे शहरों में काम करना ही बेहतर समझा. इस फैसले से इन लोगों के लिए स्थिति में नहीं के बराबर ही बदलाव आ पाएगा.

लेकिन मेरठ के दंगों में पीएसी की भूमिका की एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा खिचाई और औरतों के खिलाफ अपराधों की वृद्धि के गृह मंत्रालय के मूल्यांकन के साथ ही आए इस फैसले से पुलिस दमन के मामले पर प्रकाश पड़ेगा और इसमें सुधार की जरूरत महसूस होने लगेगी.

1980 में पुलिस की क्रूरता के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व करने वाले विपक्षी नेता मधु लिमये ने कहा, "राजीव और उनके पूर्ववर्तियों के शासन में एक व्यवस्थित राज्य नृशंस राज्य में बदल गया है. इस मामले की तरह ही वकील संगठन तथा अदालतें व्यवस्थित राज्य की बहाली में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं."

—पंकज पचौरी, बुलंदशहर और गाजियाबाद से

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गोवा

भंवर में नैया

अदालती फैसले से मुश्किल बढ़ी

लगता है आजकल मुख्यमंत्रियों के लिए मौसम खराब चल रहा है. आंध्र प्रदेश में हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री नंदमूरि तारक रामराव की खिंचाई कर दी, तो राजस्थान में हरिदेव जोशी का तख्ता रातोरात पलट गया. और अब गोवा के एक भू-अधिग्रहण अधिकारी लुकाज एफ. बोथेलो के कार्यकलापों के खिलाफ अदालती फैसले के कारण मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे का भी भाग्य अधर में लटक गया है.

यह मामला अभूतपूर्व है. उत्तरी गोवा के एक जमींदार परिवार ने भू-अधिग्रहण अधिकारी बोथेलो के उस फैसले को चुनौती दी जिसमें उसकी जमीन के अधिग्रहण के एवज में राज्य सरकार ने इंकाई मुख्यमंत्री की मां को मुआवजा दे दिया है. इस मामले में बंबई हाईकोर्ट के जज पी.बी. सावंत का फैसला आने के बाद राजधानी पणजी में राजनैतिक गतिविधियां तेज हो उठी हैं. विधानसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया. और राजधानी की सड़कों पर बाकायदा पोस्टर—युद्ध शुरू हो गया. राणे के पक्ष और विपक्ष में दिए विज्ञापनों से अखबार अटे जा रहे हैं.

राणे की मुश्किलें पिछले महीने शुरू हुईं जब न्यायाधीश सावंत ने बंबई हाईकोर्ट की पणजी पीठ के दो न्यायाधीशों के अलग-अलग फैसलों पर अपना अंतिम निर्णय दिया. इस विवाद का केंद्र दाजी दुबाशी और उनके पांच रिश्तेदारों द्वारा दायर की गई एक याचिका है. दुबाशी परिवार ने उत्तरी गोवा में एक सिंचाई परियोजना के लिए 3,000 वर्ग मीटर से भी ज्यादा जमीन के अधिग्रहण के एवज में राणे की मां मनोरमा बाई को 97,819 रुपए का मुआवजा देने को चुनौती दी थी. राणे तथा दुबाशी दोनों ही परिवार सैक्वेलीम के निवासी हैं. वहां दुबाशी परिवार ने खेती की एक बड़ी जमीन पर अपनी मिल्कियत का दावा किया था. लेकिन बोथेलो ने उनके दावे को नवंबर 1986 में रद्द कर राणे की मां को मुआवजा दे दिया.

हालांकि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को इस मामले में मुख्यमंत्री की बदनीयती के सबूत नहीं मिले लेकिन उन्होंने फैसले में साफ-साफ लिखा कि बोथेलो को दुबाशी परिवार की यह गुजारिश नामंजूर नहीं करनी चाहिए थी कि भूमि विवाद निबटारे के लिए जिला अदालत में भेज दिया जाए. न्यायाधीश सावंत ने इस बात पर भी सख्त नाराजगी जाहिर की है कि दुबाशी सरकारी आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर करने जा रहे हैं, यह जानते हुए भी बोथेलो पणजी में मुख्यमंत्री के सरकारी बंगले पर गए और 12 दिसंबर 1986 को उन्हें मुआवजे का चेक सौंप आए.

उधर बोथेलो और राणे दोनों का कहना है कि मुख्यमंत्री द्वारा अपने निवास पर

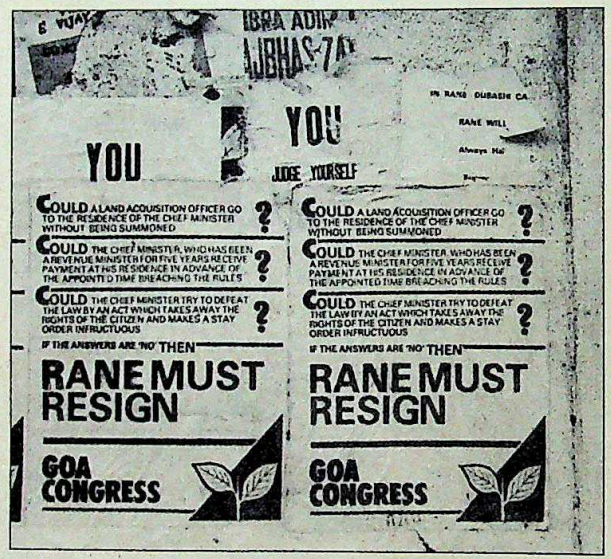

पोस्टर-युद्ध; राणे (ऊपर दाएं); और दुबाशी

रकम लेने का रिवाज हमेशा से चला आ रहा है. मुआवजे के भुगतान में की गई जल्दबाजी के लिए अदालत ने भू-अधिग्रहण अधिकारी की खिंचाई की.

विपक्षी दलों ने इसका पूरा फायदा उठाया और राणे तथा उनकी सरकार के खिलाफ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया. 31 सदस्यों की विधानसभा में इंका विधायकों की संख्या 17 है इसलिए गोमांतक पार्टी और गोवा कांग्रेस के विधायकों के पास अविश्वास प्रस्ताव पर 7 घंटे की धुआंधार बहस के बाद वाकआउट करने के सिवाय कोई रास्ता ही नहीं बचता था. पर गोवा के एक प्रमुख इंका नेता विल्फ्रेड डिसूजा ने राणे को बरखास्त करने के लिए प्रधानमंत्री को तार भेजा है. उन्होंने कहा, "आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री रामराव के खिलाफ टिप्पणियां की तो वहां इंका उनसे इस्तीफे की मांग करने लगी है. क्या यही सिद्धांत राणे के मामले में भी लागू नहीं किया जाना चाहिए?" राणे ने मुआवजे की रकम जिला अदालत में जमा करवा दी है. अब यह अदालत साल भर के अंदर इस अभूतपूर्व मामले का फैसला करेगी.

लेकिन राणे को मुख्य चुनौती अपनी ही पार्टी के भीतर से मिल रही है. ठीक साल भर पहले जब भाषाई दंगों के बाद उनके पांच में से चार मंत्रियों ने बगावत कर दी थी तब आलाकमान ने वह विद्रोह कड़ाई से कुचल दिया था. हालांकि न्यायाधीश सावंत के फैसले में राणे की बदनीयति पर शंका नहीं की गई है फिर भी असंतुष्टों को तो मौका मिल ही गया है. कहा जाता है कि 12 इंकाई विधायकों ने मुख्यमंत्री के खिलाफ एक ज्ञापन पर दस्तखत किए हैं, और अफवाहों के अनुसार प्रदेश इंका की बैठक में भी एक अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाना था. लेकिन सरहदी गांधी के निधन के कारण यह बैठक टल गई.

उधर राज्य के कई वरिष्ठ इंका नेताओं ने राणे से इस्तीफा मांगने के लिए नई दिल्ली जाकर पार्टी आलाकमान को मनाने की कोशिश भी की. हालांकि पिछले साल मुख्यमंत्री पद के मुख्य दावेदार रहे बिजली-मंत्री हरीश जांते पिछले पखवाड़े दिल्ली में थे. लेकिन आलाकमान का रवैया हमेशा की तरह अबूझ बना रहा. पिछले साल जून में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद से विधानसभा के नए चुनाव कराने की मांग की जा रही है, खासकर इसलिए भी कि विधानसभा क्षेत्रों की संख्या अब बढ़कर 40 हो जाएगी. पर आलाकमान को गोवा के मुख्यमंत्री के भाग्य का फैसला करते वक्त में पार्टी को कौन विजय दिलाएगा.

—एम. रहमान

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गुजरात

देहगांव में गुरु की देहलीला

अखबारों में मामला उछलने के बावजूद गुरु का असर कायम

स्वभाव से शांत और मधुर, 39 वर्षीय वैष्णवाचार्य कलानिधि गोस्वामी अहमदाबाद के निकट छोटे-से कस्बे देहगांव में बने राधा-वल्लभ मंदिर के प्रधान हैं. लेकिन इस धार्मिक पृष्ठभूमि के बावजूद पिछले महीने एक सनसनीखेज कांड की लपेट में वे आ गए. उन पर भक्तिनों के साथ अनैतिक संबंध का आरोप है.

इस कांड का भंडाफोड़ 7 जनवरी को हुआ, जब गुजरात के एक प्रमुख दैनिक के स्तंभकार देवेंद्र पटेल ने 'गुरु जी' की कथित करतूतों पर एक लेख छपवाया. इस लेख के साथ जो फोटो छापे गए उनमें अहमदाबाद के एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर और उद्यमी पार्थिव अध्यारु की 38 वर्षीया खूबसूरत पत्नी वैदेही और गुरु को कामक्रीड़ा की मुद्राओं में दिखाया गया था. और मजेदार बात तो यह है कि ये फोटो उस वीडियो फिल्म के हैं जिसे वैदेही के पति ने खुद तैयार किया था.

जहां एक ओर गुरु को सार्वजनिक आलोचना का शिकार होना पड़ा, वहीं कई लोगों ने यह सवाल भी उठाया कि कहीं अध्यारु ने गोस्वामी को फंसाने के लिए तो पत्नी का इस्तेमाल नहीं किया?

वैदेही पहली बार 1986 के मध्य में गोस्वामी के संपर्क में आई. तब गुरु जी ने भविष्यवाणी की थी कि यदि उसने अनुष्ठान नहीं किया तो एक साल बाद पति उसे तलाक दे देगा. इस पर वैदेही नियमित रूप से देहगांव जाने लगी. अचानक एक दिन उन्होंने वैदेही को बताया कि वे पिछले जन्म में उसके पति थे. और यदि वह उनके साथ शादी कर ले तो उसे मोक्ष मिल जाएगा और उसका पति भी उसे नहीं छोड़ेगा. गोस्वामी ने भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने वैदेही से 'विवाह' भी कर लिया.

लेकिन जल्दी ही वैदेही को पता चला कि उसके भाई संजय पारीख की पत्नी श्यामा

गोस्वामी (नीचे) और उनके घर के सामने प्रदर्शन करती महिलाएं

उनके पूर्व जन्मों का पति होने का दावा करके कलानिधि गोस्वामी अपनी महिला अनुयायियों के साथ अनैतिक संबंध कायम कर लिया करता था

भी गुरु जी से मिलने के लिए देहगांव जाया करती है. श्यामा ने बताया कि पिछले जन्म में गोस्वामी उसका पति था. तब कहीं जाकर दोनों महिलाओं को समझ आया कि शादीशुदा और दो बच्चों का पिता गोस्वामी दोनों का दैहिक शोषण कर रहा है.

इसके बाद वैदेही ने अपने पति को विश्वास में लिया और दोनों ने मिलकर गुरु को फांसने की योजना बनाई. पिछले साल अक्तूबर में वैदेही ने गोस्वामी को टेलीफोन कर अहमदाबाद के अपने बंगले में यह कहकर बुलाया कि उसके पति 'बाहर' जा रहे हैं. जैसे ही गुरु वहां पहुंचे, वैदेही उन्हें अपने सोने के कमरे में ले गई. उधर उसके पति अध्यारु ने पहले से ही कमरे के रोशनदान पर वीडियो कैमरा लगा रखा था. इस तरह 'उस' अवस्था में गोस्वामी और वैदेही की तस्वीरें उतार ली गईं.

अध्यारु ने पिछले साल दिसंबर में अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर एस.एन. सिन्हा को इस वीडियो कैसेट की जानकारी दी लेकिन पुलिस ने जब कुछ नहीं किया तो वह अखबारवालों के पास जा पहुंचा. अध्यारु ने कहा, "मैं इस तरह के फरेबी स्वामियों से भोली-भाली औरतों को सावधान करना चाहता था."

लेकिन इस सब पर गोस्वामी कुछ और ही किस्सा बयान करते हैं. उनका कहना है कि उन्हें वैदेही से हमबिस्तर 'दबाव में आकर' होना पड़ा. उनके अनुसार अध्यारु का मकसद उन्हें ब्लैकमेल करना था. उन्होंने दावा किया, "इस मामले को रफा-दफा करने के लिए पहले उन लोगों ने 7 लाख रुपए की मांग की." पर बाद में उनका यह भी कहना है कि उन्होंने वैदेही के भाई संजय पारीख को अपने एक चेले एस.बी. सिंह की कंपनी 'जे. बालाजी ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड' का पार्टनर बनने में' भी मदद की थी. उनके अनुसार पिछले साल पारीख ने फर्म से खुद को अलग कर लिया और उस पर एस.बी. सिंह के ऊपर 14 लाख रुपए का कर्ज भी चढ़ गया. उन्होंने कहा, "अध्यारु और पारीख वीडियो कैसेट को जाहिर कर देने का डर दिखाकर मुझे एस.बी. सिंह को कर्ज की रकम छोड़ देने के लिए राजी करने को बाध्य कर रहे थे." हालांकि गोस्वामी यह तो कहते हैं कि उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है, लेकिन अभी तक वे मामले को अदालत में नहीं ले गए हैं.

लेकिन संभोग करते हुई खींची गई तस्वीरों का असर देहगांव में गोस्वामी के चेलों पर पड़ता हुआ नहीं दिखता. सूरज ढलते ही गुरु जी के घर लोगों का तांता लगा जाता है और सभी शिष्य और शिष्याएं उनके चरणों पर गिरने को तैयार रहते हैं.

—उदय माहूरकर, देहगांव में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

राजकोट में भूख हड़ताल

गुजरात

कलाकार खफा

मंत्री फिर भी नहीं मानते

जब राजनैतिक नेताओं की कहीं घुसपैठ होती है तो वहां से लेखक बाहर हो जाते हैं. गुजरात में यही हो रहा है. वहां के शिक्षामंत्री हंसमुखभाई पटेल राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित कला और साहित्य की अकादमियों पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं.

ऐसी पांच अकादमियों के अध्यक्ष पटेल उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं और लेखक तथा कलाकार उनके खिलाफ मोर्चा बांधे हुए हैं. उन्होंने जामनगर, नाडियाड और राजकोट जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन और भूख हड़ताल की है. अब उन्होंने दूसरे जिला मुख्यालयों तक भी आंदोलन ले जाने की योजना बनाई है. आंदोलन कर रहे लेखकों और कलाकारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त लब्धप्रतिष्ठित साहित्यकारों—उमाशंकर जोशी और अशोक हर्ष का भी समर्थन प्राप्त है.

इस आंदोलन का नेतृत्व गुजरात कलाकार संघ और अंतर भारतीय साहित्य बंधुत्व जैसी संस्थाओं से जुड़े 59 वर्षीय उपन्यासकार तथा कवि नरेंद्र दवे कर रहे हैं.

पटेल जिन पांच अकादमियों पर काबिज हैं उनमें से दो—ललित कला अकादमी और गुजरात संगीत नाटक नृत्य अकादमी—पर छठे दशक में इनके निर्माण के समय से ही राजनैतिक नेताओं का कब्जा बना हुआ है. तभी से इसकी मुखालफत भी चल रही है. 1986 के मध्य में जब दो नई अकादमियां—सिंधी अकादमी और उर्दू अकादमी—बनीं तो पटेल ने विरोध पर कान न देने का फैसला कर लिया और तमाम विरोधों के बावजूद उनके प्रमुख वे खुद ही बन बैठे. फिर पिछले साल जून में उन्होंने गुजराती साहित्य अकादमी के अध्यक्ष की कुर्सी पर भी इसी तरह अपना कब्जा जमा लिया.

विरोध में करीब एक दर्जन लेखक गुजराती साहित्य अकादमी से अलग हो गए. यही तेवर दूसरे लेखकों ने भी अपनाया और दनादन इस्तीफे आने लगे. सिंधी अकादमी से सभी पांच लेखकों ने सदस्यता वापस ले ली. और उर्दू अकादमी से भी दो लेखकों ने इस्तीफा दे दिया.

हंसमुख पटेल: मजबूत पकड़

मंत्री की कारगुजारियों पर दूसरे लोग और भी खुलकर बोले. साहित्यिक बिरादरी से करीबी रिश्ता रखने वाले पूर्व सांसद पुरुषोत्तम मावलंकर ने कहा, "ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंत्री बन जाने से ही पटेल को इन साहित्यिक संस्थाओं का अध्यक्ष बनने का अधिकार मिल जाता है."

पटेल पर इन अकादमियों में राजनैतिक नेताओं को भरने के भी आरोप हैं. इस वजह से भी आलोचना के स्वर और मुखर हो उठे है. मसलन सिंधी अकादमी में एक विधायक और एक पार्षद सहित कम-से-कम चार नेताओं को नामजद किया गया है. इन अकादमियों का बजट भी अच्छा-खासा होता है. अकेले गुजराती साहित्य अकादमी का ही बजट तीन साल की अवधि के लिए 50 लाख रुपए है. ये अकादमियां चूंकि सांस्कृतिक गतिविधियां करती हैं इसलिए इनमें अहम भूमिका लेखकों और कलाकारों की ही होनी चाहिए.

इन आंदोलनों को व्यापक जन-समर्थन मिल रहा है. लेकिन पटेल का मानना है कि उन्होंने सार्वजनिक हित में ऐसा किया. उनका कहना है, "लेखकों या कलाकारों के अकादमियों के अध्यक्ष बनने से निर्णयों पर अमल में देर लगती है क्योंकि अमल करने का काम तो सरकारी तंत्र का ही है."

मंत्री का कहना है कि दवे को गुजराती साहित्य अकादमी का अध्यक्ष नहीं बनाया गया इसीलिए वे आंदोलन चला रहे हैं. लेकिन दवे इस आरोप का खंडन करते हैं, "यदि मैं कहूं कि पटेल के साथ मेरे व्यक्तिगत झगड़े हैं तब भी इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमारी लड़ाई सिद्धांतों के लिए है."

कला अकादमियों की स्वायत्तता की लड़ाई काफी पुरानी है. सातवें दशक के मध्य में तत्कालीन मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल ने स्वायत्तता की मांग मंजूर कर ली थी लेकिन इस पर अमल करने के पहले ही उन्हें अपने पद से हट जाना पड़ा.

अब पटेल ने पुराना मुद्दा फिर उभार दिया है. लेकिन आंदोलनकारी इस बार पीछे हटने के मूड में नहीं हैं. वे इस मामले को राज्यपाल आर.के. त्रिवेदी और मुख्यमंत्री अमर सिंह चौधरी तक ले गए हैं. लेकिन उनको लगता है कि मुख्यमंत्री इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे. कहा जाता है कि पटेल और चौधरी में अनबन है क्योंकि शिक्षामंत्री को पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी के गुट का माना जाता है. अगर पटेल अपने को बड़े झमेलों में उलझा लेते हैं तो चौधरी को इससे खुशी ही होगी. और शिक्षामंत्री बड़े झमेले में तो उलझते ही जा रहे हैं.

—उदय माहूरकर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शाहीं ने बनाया आशियां अपना

आर.सी. साह

भोपाल के इकबाल मेमोरियल पार्क में लगा 'शाहीं' (बाज जैसा पक्षी) का बुत मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा की परेशानी का सबब बन गया है. इस पक्षी के शिल्पकार तथा मशहूर कलाकार जे. स्वामीनाथन को पिछले पखवाड़े वोरा की एक संक्षिप्त चिट्ठी मिली. इसमें उन्होंने लिखा है कि पिछले तीन सालों से मौसम की मार के कारण इस बुत की शक्लो-सूरत बिगड़ गई है और लोग उसका मजाक उड़ाने लगे हैं. भारत भवन के निदेशक स्वामीनाथन ने शाहीं की यह मूर्ति उर्दू शायर इकबाल की याद में 3.6 लाख रुपए खर्च करके गढ़ी थी. वोरा ने स्वामीनाथन को आदेश दिया है कि "शाहीं की सही शक्लो-सूरत फिर से कायम करने का इंतजाम किया जाना चाहिए."

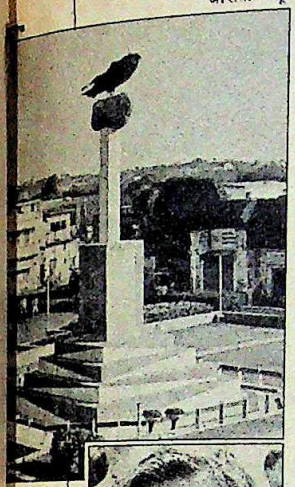

शाहीं का बुत और स्वामीनाथनः सुंदरता का सवाल

इस चिट्ठी से स्वामीनाथन बहुत नाराज हुए. उन्होंने मूर्ति की आलोचना पर अफसोस जाहिर करते हुए वोरा के आदेश पर अमल करने से इनकार कर दिया. वे तो यह मानने के लिए भी तैयार नहीं हैं कि बुत की शक्लेा-सूरत बिगड़ गई है. उनका कहना है कि मूर्ति भद्दी दिखती है 'क्योंकि इसे सुंदर दिखने के लिए बनाया ही नहीं गया.' भोपाल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष 74 वर्षीय ममनून हसन खां उनका समर्थन कर रहे हैं. उन्होंने वोरा को इस विवाद से परे रहने की सलाह दी है. पर लगता है शाहीं आगे भी विवाद का सबब बनता रहेगा.

मारेंगे फिर डुबोएंगे...

पिछले विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री राजीव गांधी के 'नूतन बांग्ला' के नारे से प्रभावित पूर्व केंद्रीय मंत्री गनी खां चौधरी उसी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में चल पड़े हैं. वे सिर्फ 'माकपा को बंगाल की खाड़ी में फेंक देने' की धमकी ही नहीं दे रहे हैं बल्कि हिंसा का रास्ता अख्तियार करने की भी अपील कर रहे हैं क्योंकि पूर्व मंत्री के अनुसार महात्मा गांधी ने हिंसा के रास्ते पर चलने के मामले में रजामंदी जाहिर की थी. वे जन-जागरण अभियान के दौरान इंकाई कार्यकर्ताओं को सलाह दे रहे हैं कि वे स्टेनगन उठा लें और हर इंकाई कार्यकर्ता की हत्या के बदले 10 मार्क्सवादियों का सफाया कर दें. जनसभाओं में वे कहते हैं, "हम लोकतंत्र की फिर से बहाली के लिए गंगा का पानी लाल कर देंगे. माकपा को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि इंका कायरों की पार्टी नहीं है."

गनी खांः हिंसा को उकसावा

हालांकि चौधरी के इन बयानों पर इंका के राज्य स्तर के नेता चुप्पी साधे हुए हैं. लेकिन कुछ तो महसूस करते ही हैं कि उग्र बयानों से चौधरी सिर्फ पार्टी की छवि बिगाड़ ही रहे हैं.

नामुराद नौकरशाह

गुजरात के मुख्यमंत्री अमर सिंह चौधरी ने अनजाने में ही सही अपनी हार कबूल कर ली है. समर्थकों और असंतुष्टों दोनों की तरफ से ही उन पर यह आरोप लगाया जाता रहा है कि राज्य प्रशासन, खासकर अफसरशाहों पर उनकी पकड़ कमजोर है. इन आरोपों से बाध्य होकर उनकी सरकार ने निचले स्तर के अफसरों को एक सर्कुलर भेजकर उनसे मंत्रियों के आदेशों पर अमल करने को कहा है.

प्रमोद पुष्करणा

अमर सिंहः कार्रवाई

मुख्यमंत्री पर नाराज नागरिकों और इंकाई नेताओं की तरफ से दोतरफा दबाव पड़ रहा था. इन लोगों का कहना था कि निचले स्तर के अफसर कैबिनेट मंत्री तक के आदेशों की परवाह नहीं करते इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए. यह मामला विधानसभा के पिछले सत्र में भी उठा था. हाल ही में मंत्रिमंडल की बैठक में भी मंत्रियों ने ऐसे अफसरों द्वारा अपने आदेशों का पालन न करने की शिकायत की. हाल ही में भेजे गए परिपत्र में इस तथ्य का खास तौर पर जिक्र किया गया है कि छोटे अफसरों ने पहले तो मंत्रियों के कुछ आदेशों को ताक पर धर दिया पर जब वही आदेश बड़े अफसरों ने दुबारा दिए तो उन पर तुरत-फुरत अमल कर दिया गया. निश्चित ही गुजरात की यह स्थिति नए टीवी सीरियल 'यस प्राइम मिनिस्टर' की स्थितियों से भिन्न नहीं है.

किसान बनेंगे बाबा के सिरदर्द

1988 में बिहार के मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे के लिए किसान नए सिरदर्द के रूप में उभर सकते हैं. भारतीय कृषि उद्योग संघ के नाम से रोहतास जिले में एक शक्तिशाली लॉबी बन रही है.

एक संपन्न किसान रणजीत सिंह राणा के नेतृत्व में किसानों ने रोहतास जिले के भभुआ में 5 जनवरी को विशाल प्रदर्शन किया. उनकी योजना है कि वाराणसी से पटना तक पैदल मार्च किया जाए.

कृष्ण मुरारी किंगर

भभुआ में किसानों की सभाः नया उभार

पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र ने भी किसानों का मामला उठाया है. पिछले पखवाड़े उन्होंने बिहार सरकार की किसान विरोधी नीतियों को उजागर करने के लिए कई रैलियों का आयोजन किया. उन्होंने 1988 को 'किसानों का साल' घोषित किया. कई राजनैतिक नेताओं का मानना है कि किसानों के मुद्दों का उठना इंका के लिए विधानसभा चुनावों में घातक हो सकता है.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

राजस्थान

निकले बड़े बेआबरू होकर

हरिदेव जोशी को दिल्ली दरबार की राजनीति लील गई

पिछले पखवाड़े अचानक ही राजस्थान के मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी पद से हटा दिए गए. हैरानी इस बात की है कि न तो वे किसी विवादास्पद कांड से जुड़े थे और न ही वहां के विधायक उनके विरुद्ध थे. पार्टी में अब सवाल उठने लगे हैं कि दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की भी क्या यही गति होने वाली है. फीचर संपादक ***इंद्रजीत बधवार*** *दिल्ली में इंका पदाधिकारियों और वरिष्ठ संवाददाता* ***पंकज पचौरी*** *जयपुर में इस घटना में शामिल नेताओं से मिले. उनकी रिपोर्ट:*

"सरिस्का के एक बाघ ने दूसरे बाघ से क्या कहा?"

"खाने के मामले में मुझे तो मुख्यमंत्री ही सबसे ज्यादा पसंद है. एक तो वे सुस्त होते हैं; दूसरे, वे काफी मोटे-ताजे होते हैं; और फिर उनके रीढ़ की हड्डी भी नहीं होती."

यह है वह लतीफा जो आजकल जयपुर में चटखारे लेकर सुनाया जा रहा है. यह सुनने में भले अक्खड़ लगे पर यह उन हालात को बयान करने के लिए काफी है जिनके चलते राजस्थान के खाए-खेले नेता हरिदेव जोशी को बेआबरू होकर गद्दी छोड़नी पड़ी. हैरानी की बात तो यह थी कि इंका के एक अल्पसंख्यक गुट के विरोध के आगे उन्होंने बिना किसी चूं-चपड़ के घुटने टेक दिए.

लेकिन 20 जनवरी को अपने विदाई भाषण में जोशी ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे इस कारण पद नहीं छोड़ रहे कि उन्हें बहुमत का समर्थन नहीं रहा बल्कि इसलिए कि उनके सिर पर एक बड़ी तोप तनी हुई है. 34 महीने बाद अपना पद छोड़ते हुए उनका कहना था, "क्योंकि आलाकमान ने मुझे आदेश दिया है और केंद्र से आए पर्यवेक्षकों ने विधायकों से बातचीत करने के बाद अपनी राय जाहिर की है इसलिए मैं राज्य के विधायक दल के नेता के रूप में श्री शिवचरण माथुर के नाम का प्रस्ताव करता हूं."

इसके तुरंत बाद ही इंका के प्रचार अभियान में यह दिखाने की कोशिश की गई कि यह एक साफ-सुथरा और व्यवस्थित परिवर्तन है. लेकिन जोशी ने जिस कटाक्ष भरे अंदाज और आधे मन से अपने खिलाफ साजिश करने वाले एक प्रमुख विरोधी का नाम प्रस्तावित किया उसे देखते हुए यह प्रचार चल नहीं पाया.

यदि पार्टी आलाकमान ने सचमुच बहुमत के बूते पर नए मुख्यमंत्री का चुनाव किया होता तो तय है कि जोशी के स्थान पर माथुर को नियुक्त नहीं किया जा सकता था. इंका ने जो चार पर्यवेक्षक जी.के. मूपनार, बी. शंकरानंद, नरेशचंद्र चतुर्वेदी और रघुनंदनलाल भाटिया—जयपुर भेजे उनका काम भी इस बात की व्यवस्था करना था कि नेतृत्व बदल दिया जाए.

लगभग 65 विधायकों ने संकेत दिया था कि नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में उनका समर्थन जोशी के प्रबल पक्षधर तथा उनकी सरकार में राजस्व तथा परिवहनमंत्री रहे हीरालाल देवपुरा को मिलेगा. बाकी विधायक माथुर, पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया और राजेश पायलट के समर्थन

माथुर: राजनीति में ऊंची छलांग

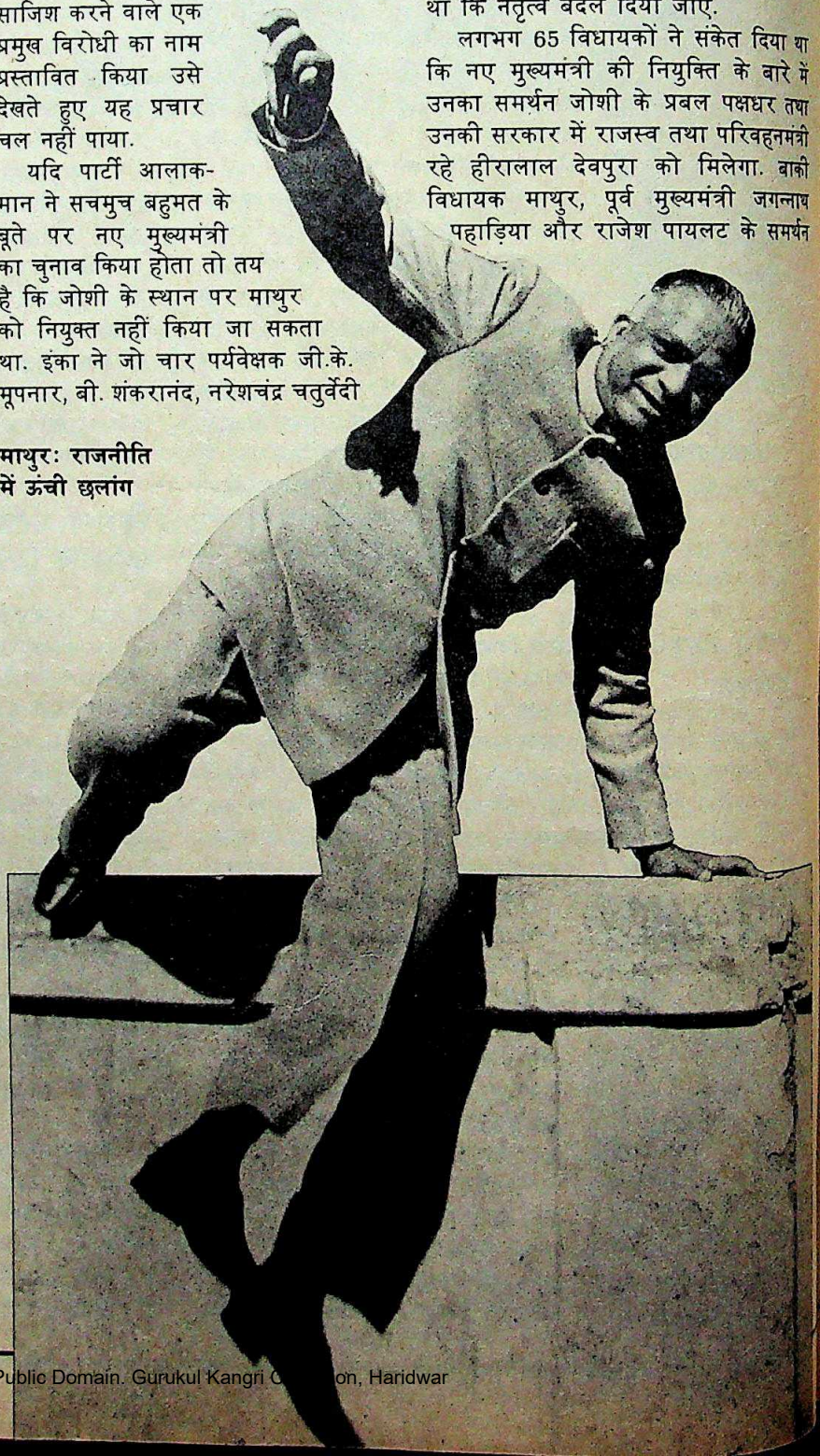

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सभी फोटो प्रशांत पंजियार

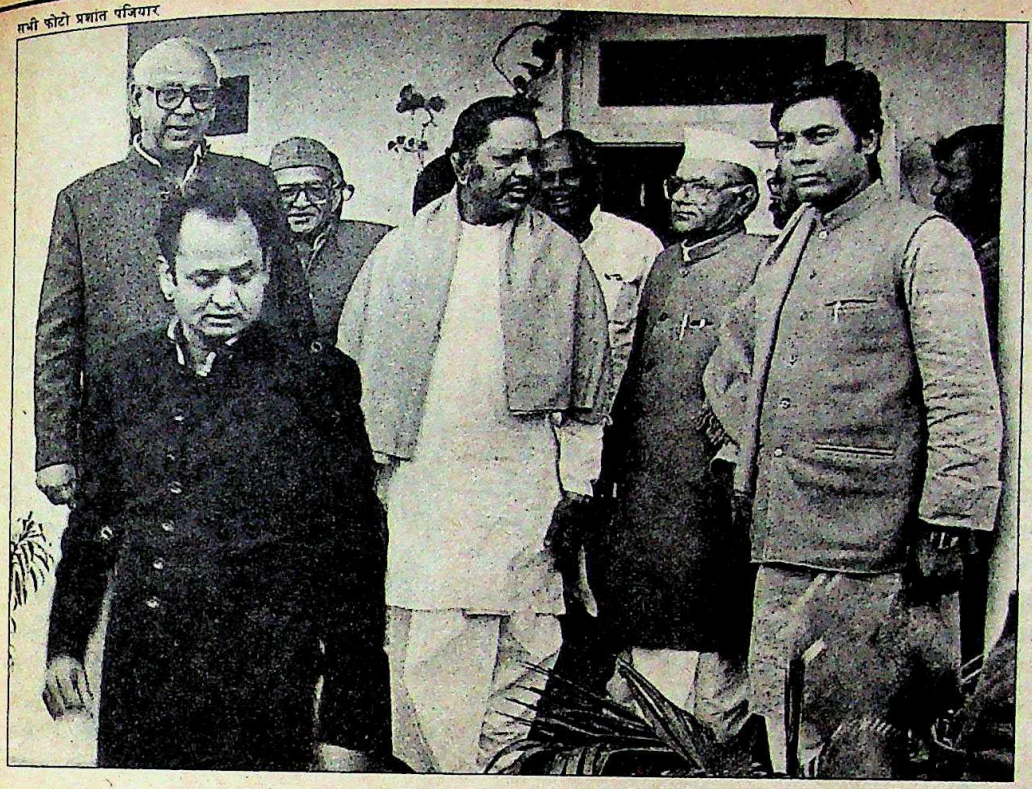

केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ जोशी (दाएं से दूसरे)

राजस्थान में मुख्यमंत्री के परिवर्तन की पूरी घटना दिल्ली दरबार में फैली जी-हुजूरी को ही उजागर करती है जिसने पार्टी के भीतर ही लोकतंत्र का गला घोंट डाला है

में बंटे हुए थे. इससे जोशी के उस दावे की ही पुष्टि हुई जो पद से हटाए जाने से कुछ दिन पहले उन्होंने किया था. आगे होने वाली घटनाओं की भनक पाकर जोशी ने अपनी उपमंत्री बीना काक को दिल्ली में प्रधानमंत्री सचिवालय के माध्यम से राजीव गांधी को यह बताने के लिए रवाना किया था कि उनके विरोधियों का यह प्रचार आधारहीन है कि उन्हें बहुमत का समर्थन नहीं रहा.

इस दिल्ली यात्रा के दौरान काक ने राजीव के सहायक विंसेंट जॉर्ज को जोशी समर्थक 90 विधायकों की सूची देते हुए यह भी दावा किया कि जोशी को हटाए जाने के अभियान के पीछे 15 से ज्यादा विधायक नहीं हैं.

काक ने इंका के पूर्व महामंत्री राजस्थानी इंका सांसद नवलकिशोर शर्मा से भी मुलाकात की जिन्होंने जोशी को बनाए रखने की सिफारिश आलाकमान तक पहुंचाई. लेकिन जोशी का विरोध करने वालों ने, जिनमें राजस्थान से सांसद और केंद्र में गृहमंत्री बूटा सिंह, मूपनार, राज्य इंका अध्यक्ष अशोक गहलोत और सड़क परिवहनमंत्री राजेश पायलट भी शामिल थे, राजीव को यही बताया कि जोशी का अब राज्य में समर्थन नहीं रहा, लिहाजा उनके बने रहने से पार्टी का नुकसान होगा.

लेकिन खतरा केंद्र के फैसले से खड़ा हो गया. पर्यवेक्षकों को यह देखकर सदमा पहुंचा कि विधायकों का बहुमत जोशी के साथ है. माथुर को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा से सिर्फ एक दिन पहले ही गृहमंत्री गुलाब सिंह शक्तावत के घर जोशी मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों और कई विधायकों की एक बैठक हुई जिसका लक्ष्य केंद्र द्वारा नए नेता की नियुक्ति को रोकना था. बैठक में इस बात पर जोर देने का फैसला किया गया कि नए नेता का चुनाव वोट के आधार पर किया जाए.

लेकिन पर्यवेक्षकों ने पार्टी एकता के नाम पर विधायकों-मंत्रियों की यह मांग ताक पर रख दी. मूपनार और शंकरानंद जैसे पार्टी महारथियों का कहना था कि अगर विधायक अपना नेता खुद चुनने पर अड़े रहे तो पार्टी टूट भी सकती है. इस पर बाद में एक विधायक ने कहा, "पार्टी देश भर में संकट काल से गुजर रही है. इसलिए हम आलाकमान की मर्जी रखने के लिए तैयार हो गए." पर मूपनार की दोटूक टिप्पणी थी, "नो कमेंट."

बाद में 20 जनवरी को पार्टी विधायकों को एकता पर लंबा भाषण पिलाने की जिम्मेदारी शंकरानंद को सौंपी गई. भाषण के बाद उन्होंने जोशी से अपने उत्तराधिकारी का नाम प्रस्तावित करने के लिए कहा. और कुछ ही घंटे बाद केंद्र के उम्मीदवार माथुर को राजभवन में शपथ दिला दी गई.

जोशी को हटाए जाने के लिए जो चार आधिकारिक कारण दिए गए. वे हैं: वे नकारा प्रशासन हैं जो सूखा राहत के काम में अकुशलता दिखाकर उन्होंने इंका समर्थित चुनाव क्षेत्रों में नाराजगी फैला दी है. दिवराला सती कांड को महिमामंडित किए जाने पर नियंत्रण पाने के लिए उन्होंने समय पर कदम नहीं उठाए और इस तरह इंका की छवि खराब कराई, सरिस्का में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान वीआइपी स्तर के महंगे इंतजाम करके उन्होंने प्रधानमंत्री की नाराजगी मोल ली और विरोधी दलों, खास तौर से पूर्व मुख्यमंत्री भैरो सिंह शेखावत के साथ नजदीकी संबंध स्थापित किए.

यह सच है कि जोशी को एक कुशल प्रशासक नहीं कहा जा सकता. पुराने नेता होने के नाते वे अपेक्षाकृत साफ-सुथरे और सतर्क कांग्रेसी हैं. उन्होंने खुद को सरकारी जिम्मेदारियां निभाने तक ही सीमित रखा. लेकिन उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वे इतने गंभीर नहीं थे कि उन्हें इस स्तर तक अपमानित किया जाता. यदि सूखा राहत के मामले में अकुशलता को किसी मुख्यमंत्री को हटाए जाने का पर्याप्त कारण मान लिया जाए तो बिहार के मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे और ओडीसा के जानकीबल्लभ पटनायक पर गाज पहले गिरनी चाहिए थी.

सरिस्का के मामले में भी सचाई यह है कि जोशी ने ठीक वैसी ही चापलूसी की जैसी दूसरे इंकाई मुख्यमंत्री ऐसे मौकों पर किया करते हैं. और असलियत तो यह है कि जोशी को डांट पिलाने के बाद राजीव उन्हें खुश करने में भी जुट गए थे. और जहां तक विरोधी नेताओं के साथ व्यक्तिगत संबंध रखने के 'अपराध' की बात है तो इस अपराध

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बीरबहादुर सिंह को दंडित किया जाना चाहिए जो लोकदल और भाजपा नेताओं के साथ पींगें बढ़ाने के लिए कहीं ज्यादा चर्चित हैं.

बूटा सिंह के साथी जोशी की अनबन लंबे समय से चल रही थी. राज्य के तत्कालीन गृहमंत्री शक्तावत ने अधिकारियों की नियुक्तियों के बारे में केंद्रीय गृहमंत्री की सिफारिशें नहीं मानी थीं. मसलन बूटा सिंह ने बलात्कार के आरोपों के चलते मुअत्तल एक आइपीएस अधिकारी को बहाल करने को कहा था. लेकिन जोशी ने उनकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया . इतना ही नहीं, उन्होंने बूटा सिंह के एक और आदमी तथा गंगानगर के पूर्व विधायक दूला राम को राज्य के एक निगम का अध्यक्ष बनाने से भी इनकार कर दिया था. इसके अलावा केंद्रीय गृहमंत्री के लगातार अनुरोध के बावजूद उन्होंने उनके चुनाव क्षेत्र जालोर के विधायक मांगी लाल को मंत्री नहीं बनाया. लेकिन जब राज्य के गृहमंत्री शक्तावत और जोशी ने बूटा सिंह के क्षेत्र के लिए सूखा राहत कोष में से कुछ विशेष रकम की मंजूरी की मांग भी ठुकरा दी, तब मामला तूल पकड़ गया.

इसके बाद केंद्रीय गृहमंत्री ने राज्य में मुख्यमंत्री से नाराज इंकाइयों की तलाश शुरू कर दी और गहलोत तथा माथुर में उन्हें अपने स्वाभाविक समर्थक भी मिल गए. असल में जोशी विरोधी अभियान ने पिछली जुलाई में जोर पकड़ा जब प्रदेश इंका के महासचिव सी.पी. जोशी समेत 18 विधायकों ने मुख्यमंत्री की आलोचना करते हुए ज्ञापन प्रधानमंत्री को दिया.

इस अभियान को दमदार बनाने के लिए माथुर ने 'सोशल पॉलिसी रिसर्च ग्रुप' नाम की एक स्वयंसेवी संस्था ही खोल डाली थी. इस संस्था ने एक पुस्तिका प्रकाशित की, जिसमें बताया गया कि प्रधानमंत्री द्वारा राजस्थान की जनता से किए गए वायदों को पूरा करने में जोशी सरकार एकदम नाकाम रही है. इसके साथ ही सूखा राहत की देखरेख के लिए नियंत्रण कक्ष बनाने वाली राज्य इंका केंद्र को भ्रामक सूचनाएं भेजने लगी.

परेशान जोशी दिल्ली यात्रा बीच में ही खत्म कर जयपुर लौट गए. वहां उन्होंने अखबारवालों से पूरे जोर से कहा कि उनसे इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा गया है. उनके इस बयान को बूटा सिंह ने खुली चुनौती माना. उन्होंने तुरंत ही इस विषय पर इंका के महासचिवों—मूपनार और गुलाम नबी आजाद से परामर्श किया. दूसरे दिन मानव संसाधनमंत्री नरसिंह राव के साथ इन तीनों ने ही जोशी के भाग्य का फैसला करने के लिए प्रधानमंत्री से मुलाकात की. इस बैठक के बाद मूपनार ने जोशी को फोन पर बताया कि प्रधानमंत्री उनका इस्तीफा चाहते हैं. लेकिन जोशी जोर देते रहे कि प्रधानमंत्री अपना फैसला उन्हें सीधे बताएं.

17 दिसंबर को प्रधानमंत्री सचिवालय ने जोशी को दिल्ली बुलाया. उन्हें प्रधानमंत्री से

हरिदेव जोशी

'नेताओं ने दखलंदाजी की'

इंका आलाकमान ने 1985 में 66 बरस के हरिदेव जोशी को यह सोच-कर मुख्यमंत्री बनाया था कि वे अपनी निर्विवाद छवि के कारण मजबूत, विपक्ष को उसके बाड़े में ही बांधे रख पाएंगे. विडंबना है कि उन्हीं जोशी को अब विपक्ष की मिजाजपुर्सी के आरोप में पद से हटा दिया गया है. हटाए जाने के बावजूद पिछले पखवाड़े उनके समर्थक उनकी पीठ पर हाथ रखे रहे. उखड़े-उखड़े-से जोशी ने जिस दिन चार्ज सौंपा, वरिष्ठ संवाददाता ***पंकज पचौरी*** *उनसे मिले. बातचीत के अंश :*

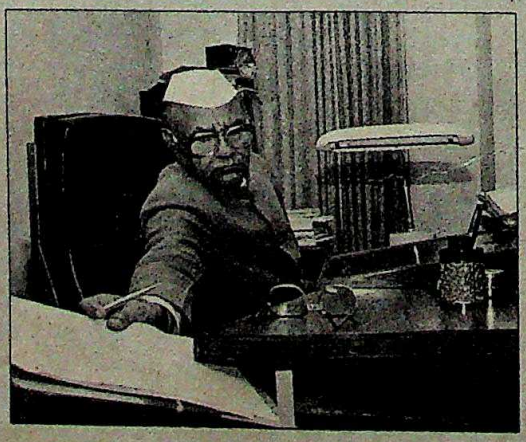

● आपने इस्तीफा क्यों दिया?

मैं पिछले दो महीनों से इस बारे में सोच रहा था. सरकार और पार्टी के बीच तनाव बहुत बढ़ गया था. पार्टी में अनुशासन भी खत्म हो चला था. सरकार को प्रशासकीय और नीतिगत मामलों पर पार्टी से कोई सहयोग नहीं मिल रहा था. सरकार तो सिर्फ नीतियां बनाती हैं, उन्हें लोगों तक पहुंचाने का काम पार्टी का होता है. मैं कब तक यह कहता फिरता कि सरकार यह कर रही है और वह कर रही है? पार्टी सिर्फ चुप्पी ही साधे नहीं बैठी थी, बल्कि सरकार के खिलाफ भी काम कर रही थी.

● अनुशासनहीनता की शिकायत आपने आलाकमान से की थी?

इस बारे में मैं अब कोई बात नहीं करना चाहता.

● केंद्रीय मंत्रियों— बूटा सिंह या राजेश पायलट ने कभी आपके काम में दखलंदाजी या कोई और समस्या खड़ी करने की कोशिश की?

बिलकुल. दखलंदाजी तो की ही, मेरे लिए समस्याएं भी खड़ी कीं.

● कैसी समस्याएं?

मुख्यमंत्रियों के सामने कैसी समस्याएं आती हैं, आप जानते ही हैं.

● आपके विचार में इस प्रवृत्ति पर रोक कैसे लगाई जा सकती है?

ये गंभीर मुद्दे हैं और इन पर गंभीरता से विचार होना चाहिए.

● आपके हटने पर आपके समर्थकों की क्या प्रतिक्रिया रही?

उन्हें बुरा लगना स्वाभाविक ही है. बेहतर होगा, इस बारे में आप उनसे ही बात करें.

● आपकी भावी योजनाएं?

काम की कमी नहीं है. मेरा अपना चुनाव क्षेत्र है, फिर राज्य भी है. अब मैं लोगों के बीच जाकर काम करूंगा.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

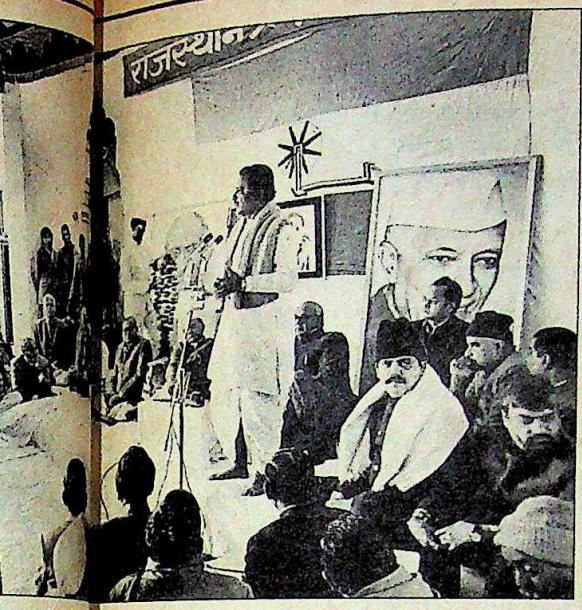

केंद्रीय नेताओं के साथ प्रदेश इंका कमेटी

मिलने के लिए पूरे 18 घंटे इंतजार करना पड़ा. आखिर 18 दिसंबर को दोपहर 3.30 बजे मुलाकात हुई. प्रधानमंत्री के साथ बैठक में बूटा सिंह, मूपनार भी थे. इसके तुरंत बाद ही जोशी जयपुर के लिए विमान पर सवार हुए. विमान में ही उन्होंने अपना इस्तीफा टाइप करवाया और हवाई अड्डे से सीधे राजभवन जाकर कार्यवाहक राज्यपाल जे.एस. वर्मा को इस्तीफा सौंप दिया.

जयपुर के 8, सिविल लाइन स्थित अपने बंगले पर पहुंचकर ही उन्होंने मूपनार को टेलीफोन पर इस्तीफे की जानकारी दी. मूपनार ने उनसे इस्तीफा देने के तरीके पर आपत्ति की. उनका कहना था कि इससे ऐसा लगेगा कि आलाकमान ने उनसे इस्तीफा दिलवाया है. बताया जाता है कि मूपनार ने जोशी से कहा कि केंद्र को परेशानी से बचाने के लिए उन्हें (इस्तीफा देने के लिए) कुछ वक्त और इंतजार करना चाहिए था.

इस पूरे प्रकरण में इतनी गोपनीयता बरती गई तथा इतने कम लोगों से सलाह-मशविरा किया गया कि इंका आलाकमान के कई सदस्य भी हैरत में पड़ गए. राजस्थान का काम देखने वाले इंका महासचिव केदारनाथ सिंह को भी न तो इस प्रकरण की जानकारी दी गई और न ही उन्हें पर्यवेक्षकों के साथ राजस्थान भेजा गया.

जोशी के विरोधी उनका पत्ता कटवाने में भले ही कामयाब हो गए हों पर उन्होंने राज्य में नई समस्याएं पैदा कर दी हैं. इस बदलाव से दलगत झगड़े कम होने के बजाय नए झगड़े खड़े हो गए हैं.

कई लोग माथुर को उनके पूर्ववर्ती की तुलना में बेहतर प्रशासक मानते हैं लेकिन उन पर एक कलंक तो लगा ही हुआ है. 1985 में डींग कस्बे में एक डीएसपी ने भरतपुर के निर्दलीय विधायक, पूर्व राजा मान सिंह की सरेबाजार हत्या कर दी गई. उसके बाद माथुर को गद्दी छोड़नी पड़ी थी. मान सिंह की सरेबाजार हत्या कर दी थी. उसके बाद माथुर को गद्दी छोड़नी पड़ी थी. इस घटना के बाद पुलिस ने उन्हें सरेबाजार घेरकर गोलियों से छलनी कर दिया था. राजस्थान के जाटों ने इस हादसे के लिए माथुर को अब भी माफ नहीं किया है. अब उनके दुबारा गद्दी संभालने से इंका को जाटों के प्रखर विरोध का सामना करना पड़ेगा. हाल में जारी किए गए सती विरोधी अध्यादेशों के कारण इंका के खिलाफ राजपूत वैसे ही भड़के हुए हैं.

अगर माथुर कोई बड़ा राजनैतिक कमाल दिखाने में कामयाब नहीं होते तो यह तय है कि अब तक 'शांत राज्य' माने जाने वाले राजस्थान में अब इंकाई असंतुष्टों और गुटबाजियों का भयंकर शोरशराबा सुनाई पड़ने लगेगा. माथुर की बहाली निश्चित ही एक अनोखी उपलब्धि है और वह भी पार्टी में एकता कायम करने के नाम पर.

शिवचरण माथुर

'कोई दखलंदाजी नहीं हुई'

*शिवचरण माथुर (61) सचेत और उदार व्यक्ति हैं. सफर पर होते हैं तो स्थानीय ढाबों पर रुकने में भी उन्हें संकोच नहीं होता. पर इस अनौपचारिक व्यक्तित्व के पीछे है एक गंभीर प्रशासक. अपनी प्रशासनिक काबिलियत की वजह से वे इंदिरा गांधी के खासमखास बने रहे. पर अबकी बार मुख्यमंत्री पद पर माथुर की सवारी आसान नहीं है. मुखालफत के स्वर उठने लगे हैं. मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली सुबह ही वरिष्ठ संवाददाता **पंकज पचौरी** से उनकी बातचीत हुई. उसी के अंश:*

• नेतृत्व में बदलाव के साथ और क्या बदलाव होने वाले हैं?

यह परिवर्तन निरंतरता बनाए रखने के लिए है. एक नेता ने दूसरे नेता के लिए गद्दी खाली कर दी है.

• क्या विधायकों का बहुमत आपके साथ है?

मुझे सर्वसम्मति से पार्टी का नेता चुना गया है. विधायकों का समर्थन न होने का सवाल ही नहीं उठता.

• परंतु पूर्व मुख्यमंत्री को पार्टी के लोगों द्वारा आलोचना के कारण जाना पड़ा.

आलोचना पार्टी के भीतर ही थी. किसी ने भी अखबार वालों के सामने मुंह नहीं खोला. अगर मैं भी गलती करूं तो मेरी भी आलोचना होनी चाहिए. मेरी चिंता यह है कि पार्टी एकजुट रहे. अगर मतभेद हैं, तो मैं उनका गला नहीं घोंटना चाहूंगा. लेकिन मतभेद पार्टी के मंचों पर ही उठने चाहिए.

• परंतु पार्टी में गुटबाजी बढ़ने का अर्थ होगा आलाकमान पर ज्यादा निर्भरता.

मैं अपनी पार्टी को खुद संभालूंगा. योग्य व्यक्तियों, पार्टी में अच्छा काम करने वालों और युवाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा.

• पूर्व मुख्यमंत्री का कहना है कि केंद्रीय नेताओं ने राज्य में दखलंदाजी की है. इस मामले में आपका रवैया क्या रहेगा?

कैसी दखलंदाजी? अगर पार्टी के बड़े सहयोगी किसी समस्या को सुलझाने की कोशिश करते हैं तो उसे किसी भी तरह से दखलंदाजी नहीं कहा जा सकता. ये तो मतभेद दूर करने की कोशिशें मात्र हैं.

• क्या विपक्ष के प्रति आप सख्त रवैया अपनाएंगे?

विपक्ष को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. मैं यह नहीं कह रहा कि विपक्ष से कड़ाई बरतनी चाहिए. मैं उससे रचनात्मक सहयोग चाहूंगा, पर अपनी पार्टी की कीमत पर नहीं.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अर्धसैनिक बल

काम के बोझ से दोहरे हुए रक्षक

न तो ठीक से प्रशिक्षण ले पाते हैं, न मन बना पाते हैं और न छुट्टियां ही मिलती हैं

जब-जब भारत में कहीं किसी तरह का जातीय या सांप्रदायिक तनाव बढ़ता है तब-तब केंद्र सरकार की एक ही प्रतिक्रिया देखने को मिलती है— तीन लाख अर्धसैनिकों की उस फौज की कुछ कंपनियों को तनाव वाले इलाके में झोंक दिया जाता है जिस पर यह देश हर साल 1000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है. अर्धसैनिक दस्तों के इस अत्यधिक उपयोग का नतीजा है कि ये जवान थके हुए रहते हैं. उधर छावनियों में न तो प्रशिक्षण के लिए जवान रहते हैं और न किसी आपात स्थिति के लिए. विशेष संवाददाता ***शेखर गुप्ता*** *ने इन अर्धसैनिक बलों और गृह-मंत्रालय के दर्जनों अधिकारियों से बातचीत के बाद यही नतीजा निकाला है कि 1991 में 1986 के मुकाबले 50 फीसदी ज्यादा सैनिक नियुक्त करने के बावजूद हालात किसी मायने में बेहतर नहीं होने जा रहे. उनकी रिपोर्ट:*

तमाम कठिनाइयों के बावजूद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जीवट की दाद ही देनी होगी. पिछले पखवाड़े इस संगठन के दस्ते ने गणतंत्र दिवस समारोह की परेड में जिस धुन पर कदम मिलाते हुए सलामी दी उसके बोल थे— 'चलते रहो प्यारे'. यह गीत किसी और ने नहीं बल्कि संगठन के महानिदेशक एस.डी. पांडे ने खुद लिखा है. गीत के इन बोलों की खासियत यह है कि 88 बटालियनों वाले इस संगठन को जिस तरह दंगे वाले एक इलाके से मुसीबत में फंसे दूसरे इलाके की ओर दौड़ाया जाता है, उसकी संगीतभरी अभिव्यक्ति के साथ-साथ ये बोल अपने लोकप्रिय नाम 'सीआरपी' का भी खासा लयात्मक प्रतिनिधित्व करते हैं.

सीआरपी की ही तर्ज पर दूसरे अर्ध-सैनिक बलों में भी ऐसे व्यंग्य प्रचलित हैं. 100 बटालियन वाले सीमा सुरक्षा बल (बार्डर सिक्योरिटी फोर्स) के सिपाही इसे 'बिस्तर संभाल फोर्स' के नाम से बुलाते हैं. संभव है कि इनकी देखादेखी असम राइफल्स और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) भी अपने लिए कोई उपयुक्त नाम खोज लें. इन संगठनों पर काम का बढ़ता दबाव देखते हुए गृह मंत्रालय अपनी आर्थिक सीमाओं के बावजूद इनमें नई भर्तियां करने को उत्सुक है. काम के दबाव के संदर्भ में पांडे कहते हैं, "मेरे जवानों ने बहुत मुसीबतें झेली हैं. इस बारे में जल्दी ही कुछ किया जाना चाहिए."

एक के बाद दूसरी कार्रवाई में झोंके जाने की इस परंपरा की ओर इशारा करते हुए सीआरपी के एक कमांडर का कहना था, "इस समय हमारे दस्ते दुनिया के सबसे सक्रिय हवाई दस्ते बन चुके हैं" उनकी बटालियन को पिछले साल 33 और उसके पहले साल 31 कार्रवाइयों में भाग लेना पड़ा था. ऐसे में जवानों का मनोबल गिरना स्वाभाविक ही है. इन्हीं हालात का नतीजा है कि हाल ही के महीनों में जवानों में अनुशासन-हीनता और यहां तक कि अफसरों पर हमले किए जाने की घटनाएं भी हो चुकी हैं. बीएसएफ के एक अधिकारी का कहना था, "युद्ध में जुटी सेना और हम लोगों में बस यही फर्क है कि हमें पता नहीं होता कि युद्ध कभी खत्म होगा भी या नहीं."

पंजाब की लगातार बिगड़ती स्थिति, दिल्ली पर पड़ने वाले उसके असर, उत्तर-पूर्व में अशांति की बुदबुदाहट और दार्जिलिंग,

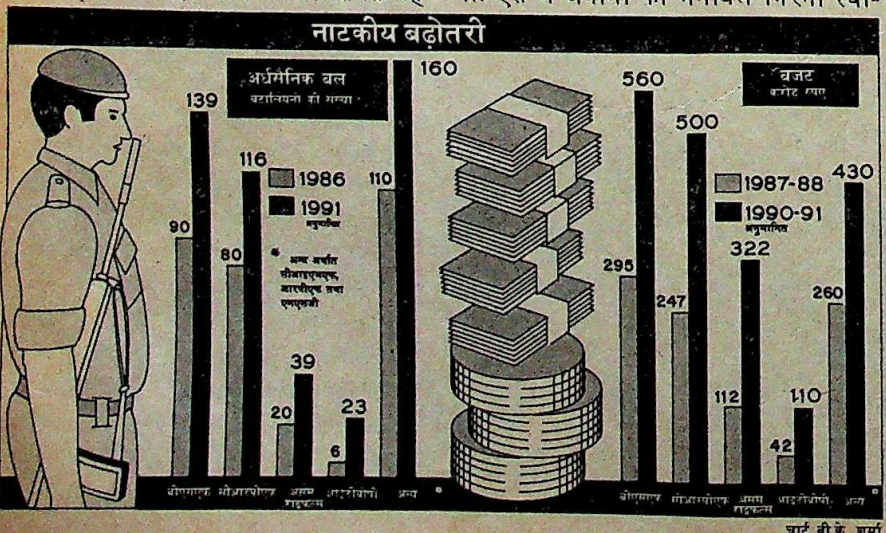

चार्ट: बी.के. शर्मा

गश्त पर सीआरपी जवान: बेहिसाब काम

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आंध्र प्रदेश तथा श्रीलंका में खुलने वाले नए मोर्चों को देखते हुए इस टिप्पणी को हल्का ही मानना होगा. गृह मंत्रालय के एक अधिकारी की टिप्पणी थी, "हर रोज किसी-न-किसी राज्य से और ज्यादा पुलिस भेजने की मांग मिलती रहती है. लेकिन यहां हालत यह है कि और जवान हैं ही नहीं."

हालात की गंभीरता का अनुमान आंतरिक सुरक्षा राज्यमंत्री पी. चिदंबरम के दफ्तर में लगे भारत के नक्शे से लगाया जा सकता है. इस नक्शे पर रंग-बिरंगे पिन लगाकर दिखाया गया है कि किस-किस स्थान पर अर्धसैनिक बलों की कंपनियां तैनात हैं. एक पिन का अर्थ है एक कंपनी यानी 100 से 150 जवान. पंजाब, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, उत्तर-पूर्व के सात राज्यों और पश्चिम बंगाल तथा आंध्र के हिस्सों में लगी हुई ढेरों पिनें देश के रंग-बिरंगे होने के एहसास के साथ-साथ यह भी संकेत देती हैं कि बुराइयों के मामले में भी इस देश की अनेकता में जबरदस्त एकता है. यहां तक कि देश की सीमा के पार भी लगभग एक दर्जन लाल पिनें देखी जा सकती हैं. श्रीलंका में सीआरपी की दो बटालियनें तैनात हैं.

अर्धसैनिक संगठनों पर काम का बढ़ता दबाव देख गृह मंत्रालय अपनी आर्थिक सीमाओं के बावजूद इनमें नई भर्तियां करने को उत्सुक है

यह असलियत कितनी भयावह है इसका अनुमान इन तथ्यों से लगाया जा सकता है:

► सीआरपी की 498 कंपनियों में से 224 पंजाब और चंडीगढ़ में तैनात हैं. पिछले पखवाड़े दिल्ली में इनकी संख्या 89, प. बंगाल (मुख्यतः दार्जिलिंग) में 25, त्रिपुरा में 30, अरुणाचल में 25 और शेष उत्तर-पूर्वी राज्यों में 45 थीं. इनके अलावा हाल ही में गठित की गई महिला बटालियन समेत 13 कंपनियां श्रीलंका में हैं और कुछ आंध्र व गुजरात में हैं. नतीजा यह है कि केंद्र में गृह मंत्रालय के पास आरक्षित कंपनियों के नाम पर कुछ भी नहीं है.

► बीएसएफ की लगभग 500 कंपनियों में से 85 पंजाब में आंतरिक शांति बनाए रखने में व्यस्त हैं. एक दर्जन कंपनियां दार्जिलिंग में ऐसे काम के लिए तैनात हैं जो उनके मूल काम से बहुत अलग है. उत्तर-पूर्व के राज्यों में इनकी संख्या तीन दर्जन है. नतीजतन भारत-पाक सीमा की चौकसी की मूल जिम्मेदारी निभाने वाली बीएसएफ की शक्ति कम हो गई है. अपेक्षा की जाती है कि बीएसएफ की 6-6 कंपनियों वाली 13 बटालियनें किसी भी आपातकाल के लिए आरक्षित रखी जानी चाहिए. लेकिन आज हालत यह है कि एक बटालियन भी आरक्षित नहीं है. और कश्मीर मोर्चे पर तो सरकार ने बीएसएफ को हटाकर सेना तैनात कर दी है. सेना का काम बढ़ गया है और उसे अपेक्षाकृत निचले दर्जे का काम भी करना पड़ रहा है.

► असम राइफल्स, सीआइएसएफ और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आइटीबीपी) का गठन अलग-अलग तरह के कामों के लिए किया गया था. लेकिन आज आंतरिक सुरक्षा कारणों से इन आरक्षित जवानों को भी दूसरे कामों में झोंक दिया गया है.

प्रमोद पुष्करणा

पिछले 6 साल में इन सुरक्षा बलों की ताकत में 30 फीसदी की बढ़ोतरी तो हुई पर उन पर काम का दबाव 1981 के मुकाबले कहीं ज्यादा हो चुका है. इस बात की भी उम्मीद बहुत कम है कि 1991 में वर्तमान महत्वाकांक्षी विस्तार योजनाएं पूरी होने पर भी हालात सुधर पाएंगे (देखें चार्ट). वर्तमान अनुमानों के अनुसार एक अर्धसैनिक बटालियन पर सालाना एक करोड़ रुपए खर्च आता है. इस पर गृह मंत्रालय के एक अधिकारी की टिप्पणी है, "तकलीफ की बात तो यह है कि इतना पैसा और जनशक्ति खर्च करके भी हमारा वातावरण शायद ही और सुरक्षित हो पाए."

उदाहरण के लिए हाल ही में सीआरपी की एक बटालियन मिजोरम में कठिन जिम्मेदारी निभाने के बाद अभी दिल्ली पहुंची ही थी कि 24 घंटे के नोटिस पर ही उसे जाफना के लिए रवाना कर दिया गया. इसके एवज में दिल्ली के लिए एक बटालियन दार्जिलिंग से मंगाई गई. लेकिन इन जवानों की विदाई के अगले ही दिन वहां हिंसा भड़क उठी. पंजाब और गुजरात से तुरंत बागडोगरा के लिए हवाई रास्ते से नई कुमुक भेजनी पड़ी.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इस समस्या का सबसे चौंकाने वाला सबूत है इंडियन एअरलाइंस की उड़ानें जो आमतौर पर समय से नहीं चलतीं. एअरलाइंस वाले इसके लिए ऊपरी तौर पर धुंध और यांत्रिक खराबी को जिम्मेदार ठहराते हैं पर इसका वास्तविक कारण अर्धसैनिक टुकड़ियों को संकटग्रस्त क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए उड़ानें भरना होता है. तय है कि जवानों को देश के एक कोने से दूसरे कोनें तक हवाई जहाजों से ले जाने में बहुत पैसा फुंकता है. इस सबमें ये जवान थककर चूर भी हो जाते हैं और उन्हें अपरिचित स्थानों पर भी काम करना पड़ता है. उन्हें कभी-कभार ही अपनी सालाना 60 दिन की छुट्टी मिल पाती है.

हालात तब और भी बदतर हो जाते हैं जब उनसे वह काम नहीं लिया जाता जिसका उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है. बीएसएफ हथियारों से लैस होती है और उसे सीमारक्षण के हिसाब से हथियारबंद किया जाता है और तदनुकूल प्रशिक्षण दिया जाता है. गुस्सैल भीड़ का सामना करने के लिए उसके पास लाठियां और पथराव से बचाने वाली ढाल भी नहीं होती. अधिकतर क्षेत्रों में सीआरपी के जवानों को सामान्य गश्त लगानी पड़ती है, जो कि पुलिस का काम है. सिर्फ दिल्ली में, सीआरपी के लगभग 2500 जवान वीआइपी लोगों के घरों के बाहर और अहम ठिकानों पर पहरा देने के लिए तैनात हैं. दूसरी ओर उत्तरपूर्व, पंजाब और जाफना में इन्हें बगावत का मुकाबला करना पड़ रहा है

रांची के हेवी इंजीनियरिंग कारखाने में दंगा होने के बाद सार्वजनिक निकायों की संपत्ति की रक्षा के लिए 1969 में सीआइएसएफ का गठन हुआ था पर आज इसकी टुकड़ियों का प्रयोग पंजाब में आंतरिक सुरक्षा, त्रिपुरा में शांति स्थापना और मेघालय में चुनावों के लिए हो रहा है, जबकि जिस कानून के तहत इसका गठन हुआ था उस कानून के अनुसार इसका प्रयोग सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के क्षेत्र के बाहर नहीं किया जा सकता.

पर सबसे ज्यादा बेहूदगी तो आइटीबीपी के साथ की गई है. हिमालय क्षेत्र में चीन से सटी सीमाओं पर गश्त करने के लिए इस विशेष बल का गठन 1962 में किया गया था. अब पंजाब और दूसरे स्थानों पर बैंकों की हिफाजत के लिए इसकी छह बटालियन तैयार की जा रही हैं. तर्क यह दिया जा रहा है कि इससे आइटीबीपी के जवानों को पहाड़ी व मैदानी क्षेत्रों में अदल-बदलकर जाने का मौका मिलेगा.

परंपरा है कि हर समय प्रत्येक बटालियन की कम-से-कम एक कंपनी का प्रशिक्षण होते रहना चाहिए. इसके मुताबिक सीआरपीएफ की 88 कंपनियों और सीमा सुरक्षा बल की 100 कंपनियों को हर समय प्रशिक्षण शिविर में होना चाहिए. पर पिछले सप्ताह इनकी क्रमशः दो और तीन कंपनियों का ही प्रशिक्षण चल रहा था.

पिछले साल गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों का एक सर्वेक्षण कराया. हर संगठन से कहा गया कि एक गुप्त पत्र में अपनी स्थिति का आकलन लिखें और साथ ही बल के आधुनिकीकरण और विस्तार की योजनाओं का ब्यौरा भी दें. सभी संगठनों ने काम की अधिकता के कारण प्रशिक्षण न होने की शिकायत की. सीआरपीएफ की रिपोर्ट में कहा गया था, "सबसे अधिक नुकसान प्रशिक्षण का ही होता है."

अभी हाल में हुई कई बैठकों में अर्द्धसैनिक बलों के मुखियाओं ने प्रशिक्षण न होने पर कड़ा विरोध जताया. चिंतित गृहमंत्री ने आदेश दिया कि सीआरपीएफ की जो 10 बटालियनें बनाई जा रही हैं उन्हें प्रशिक्षण के लिए आरक्षित किया जाए और उन्हें दूसरे कामों के लिए बाहर न भेजा जाए. इस तरह के आश्वासनों पर भरोसा न करने वाले अफसरों का कहना था कि उन्होंने ऐसी बातें कई बार पहले भी सुनी हैं.

दरअसल बदतर होती अंदरूनी हालत की वजह से सरकार अर्धसैनिक बलों में अपने बूते से अधिक जवान भरती करने के लिए मजबूर है. आग लगने पर कुआं खोदने की सरकार की प्रशासनिक शैली के अनुरूप ही सरकार सैन्य बल में बढ़ोतरी कर रही है. पर इस बात पर ठोस विचार नहीं कर रही कि अशांति क्यों बढती है.

तीन साल पहले जब पंजाब में आतंकवाद उभरा था तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का नया ढांचा खड़ा कर दिया गया. अब यह महिमामंडित कमांडो फोर्स वीआइपी लोगों की सुरक्षा के अलावा दूसरा कोई भी काम नहीं करती.

शायद यह सब फिजूलखर्ची भी काफी नहीं थी. लिहाजा अब कुछ हलकों में एक और बल के गठन की मांग की जा रही है जो जाफना और पंजाब के ऑपरेशन ब्लू-स्टार जैसी स्थिति में सेना के स्थायी सहयोगी की भूमिका निभाएगी. बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना था, "भारत अब कुछ मायनों में पुलिस राज्य बनने के बिलकुल करीब ही पहुंच गया है." पर इसके साथ ही मजाक में उनका यह भी कहना था कि इतना सब कुछ होने पर भी पूर्ण आंतरिक सुरक्षा कायम नहीं हो रही है, जो किसी परंपरागत पुलिस राज की इकलौती खूबी होती है.

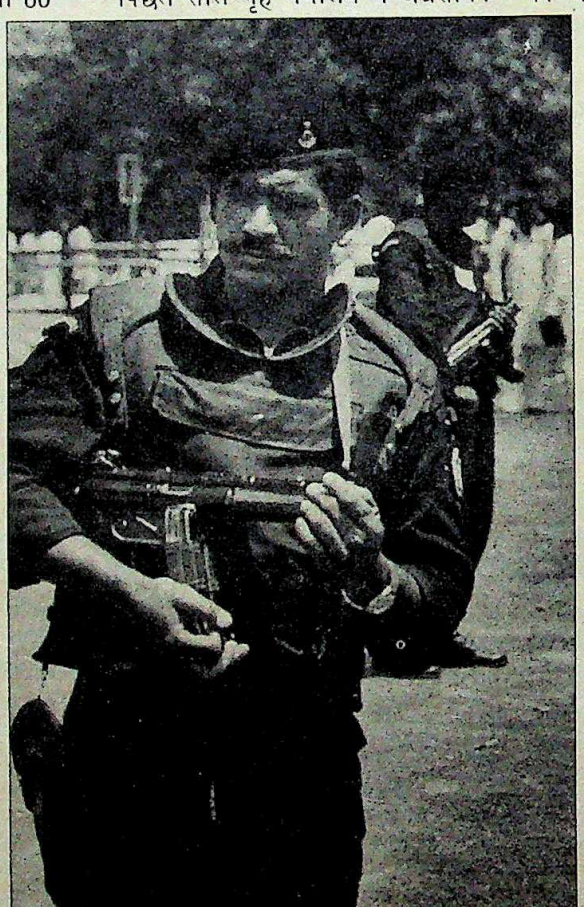

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड नामक महिमामंडित कमांडो फोर्स अब 'बड़े लोगों' की सुरक्षा के अलावा कुछ भी नहीं करती

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अमूल चॉकलेट
प्यार की मीठी भेंट

वितरक :
गुजरात को-ऑपरेटिव
मिल्क मार्केटिंग
फेडरेशन लिमिटेड, आणंद.

छ स्वादिष्ट चॉकलेट
अमूल मिल्क चॉकलेट, अमूल क्रिस्प, अमूल कॉफ़ी
अमूल फ्रूट एण्ड नट, अमूल बिटर, अमूल ऑरेंज.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तंदुरुस्ती की बढ़ती तमन्ना

दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड वाली एक सुबह. ठीक छह बजे अलार्म बज उठता है. कंबल से एक हाथ निकलकर अलार्म बंद कर देता है. पंद्रह मिनट बाद 29 वर्षीय कंपनी अधिकारी रवि नारायण दौड़ लगाने निकल पड़े हैं. वे ट्रैक सूट, माथे पर पट्टी और पैर में 'नाइक' (कंपनी के) जूते पहने हुए हैं और हाथ में एक खूबसूरत स्पीडोमीटर पकड़े हुए हैं जिससे पता चलता है कि वे कितनी दूर आ चुके हैं. दिन अभी निकलने को है और वे तैयार हो चुके हैं. वे कहते हैं, "भोर में उठना तो भारी मुश्किल है, पर इसमें फायदा बड़ा होता है. व्यायाम न करूं तो सारा दिन बदन दर्द करता है और गुस्सा आता रहता है."

बंबई में 39 वर्षीय वकील धामू मलकाणी चर्चगेट स्टेशन पर शहर के दूसरे हिस्से में स्थित एरोबिक क्लास तक पहुंचाने वाली ट्रेन के इंतजार में तेजी से चहलकदमी कर रहे हैं. उनके दोस्तों को इससे कुछ संदेह होता है. वे बताते हैं, "दोस्तों के लगता है कि मैंने कहीं और कोई महिला दोस्त रख छोड़ी है. पर उन्हें पता नहीं है कि मेरी यारी किसी महिला से नहीं एरोबिक्स से हो गई है."

त्रिवेंद्रम की 32 वर्षीया गृहिणी प्रसन्ना दयाशंकर जब कभी गणपति मंदिर में प्रार्थना करने जातीं, लोग उन्हें देखकर हंसने लगते थे. एक दिन वे हताश-सी बैठी हुई थीं. उन्होंने टीवी चालू किया तो वीना मर्चेंट का 'कीप फिट' कार्यक्रम चल रहा था. तुरंत उन्होंने खाना कम किया और एरोबिक करना शुरू कर दिया. छह महीने के भीतर ही उनका वजन 17 किलो कम हो गया.

स्वास्थ्य के मामलों में यह एक नए युग की शुरुआत है. सड़कों पर, हेल्थ क्लबों, व्यायामशालाओं, प्राकृतिक चिकित्सालयों या अपने घरों के अंदर ही रोज असंख्य भारतीय

सड़कों पर, हेल्थ क्लबों, व्यायामशालाओं या प्राकृतिक चिकित्सालयों में आज तंदुरुस्त रहने के लिए भारतीय जो कुछ कर रहे हैं, वह पहले नहीं होता था

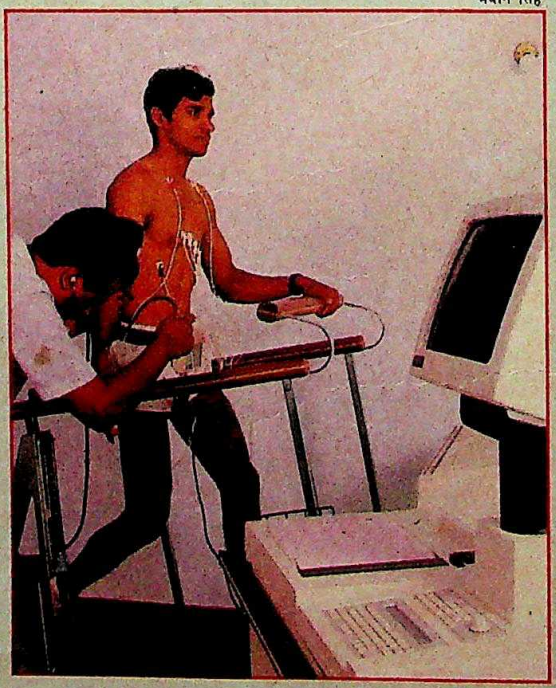

पड़ोस के पार्क में औरतों का व्यायाम (दाएं); ट्रेडमिल टेस्ट

भवान सिंह

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

चुस्त-दुरुस्त रहने के लिए वह सब कर रहे हैं जो अभी तक उनकी आदत में शामिल नहीं था. व्यस्त अधिकारियों, गृहिणियों, रईसों, तोंद निकाले घूमते व्यापारियों, बूढ़ों, जवानों, अमीरों और मध्यमवर्गीयों, सभी पर जैसे चुस्त-दुरुस्त रहने का 'बुखार' चढ़ आया है.

इसका संदेश एकदम स्पष्ट है: जाओ मोटापा, आओ जवानी. सुबह दौड़ लगाने वालों की संख्या में दस गुनी वृद्धि या स्वास्थ्य और एरोबिक केंद्र, यह सब बताते हैं कि 'देश का स्वास्थ्य' सही रास्ते पर आ रहा है. साल भर पहले दूरदर्शन ने 'दस कदम' शुरू किया था और आज ऐसे चार और कार्यक्रम विचाराधीन हैं. हर दूसरे दिन मोटापा घटाने या कम चर्बी वाला एक नया खाद्य पदार्थ या पेय बाजार में आने लगा है.

तंदुरुस्ती के प्रति लोगों में चेतना पहले धीरे-धीरे और फिर एकाएक आई है. दिल्ली और बंबई में जन्मा यह 'आंदोलन' अब परंपरावादी शहरों में भी पहुंचने लगा है. पिछले 25 वर्षों में 1000 से अधिक स्थूल-काय लोगों को उचित भोजन की सलाह देने वाले बंबई के डॉ. विष्णु कक्कड़ कहते हैं, "स्वास्थ्य के प्रति चेतना में अब 100 फीसदी वृद्धि हो गई है."

इस प्रवृत्ति की अभी की गति और दिशा से कोई संकेत मिलता है तो यही कि यह ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण होने जा रही है. लोगों में यह धारणा घर कर रही है कि चुस्त-दरुस्त आदमी ज्यादा कुशल होते हैं, खुशमिजाज होते हैं, और इस बात के संकेत हर कहीं और हर स्तर पर दिख रहे हैं:

► महाराष्ट्र के मंत्रालय और सभी सरकारी इमारतों में धूम्रपान निषेध है और इसे नहीं मानने वालों को सजा हो सकती है.

► अहमदाबाद में दस साल पहले सिर्फ एक अखाड़ा था. आज यहां दर्जन भर से ज्यादा स्वास्थ्य केंद्र हैं.

► दिल्ली से लगे सूरजकुंड में एक विशाल स्वास्थ्य झरना अगले महीने से शुरू हो जाएगा जिसका संचालन हरियाणा का पर्यटन विभाग और प्रसिद्ध सौंदर्य विशेषज्ञ शहनाज हुसैन करेंगी.

► देशभर में प्राकृतिक चिकित्सालय खुल गए हैं जो सूरज की रोशनी में पकाए भोजन से तंदुरुस्ती लाने का भरोसा दिलाते हैं.

► भारतीय खेल प्राधिकरण ने हाल ही में त्रिवेंद्रम में खेल और तंदुरुस्ती का एक बड़ा

भवान सिंह

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कार्यक्रम 'भारतीयम्' शुरू किया है जिसका लक्ष्य स्वास्थ्य संबंधी चेतना जगाना है.

लोगों की जीवन शैली धीरे-धीरे बदलती जा रही है. एअर इंडिया के एक पायलट ने एक हेल्थ क्लब में आकर अपना वजन चार पौंड कम किया ताकि उसे प्रमोशन मिल सके. कम कैलोरी वाले डिब्बा-बंद खाद्यपदार्थ 'स्लिम एड' की हर माह की बिक्री पांच लाख रुपए की है. कट्टरपंथी ब्राह्मण परिवार की श्रीमती एम. लक्ष्मी बरसों से जमी अपनी चर्बी कम करने के लिए हफ्ते में दो बार 'बॉडी रैप' में जाती हैं. कलकत्ता की एक छोटी दुकान का, जिसमें सेहत बनाने वाले खाद्य पदार्थ मिलते हैं, कारोबार जबरदस्त तरीके से चल रहा है. दिल्ली में पांच बरस पहले ट्रैक सूट ढूंढ़े नहीं मिलता था पर अब यहां इसके पांच निर्माता हो गए हैं. बंबई के पीरामल अस्पताल ने बच्चों के लिए खास कार्यक्रम तैयार किया है जिससे व्यायाम और साधारण आहार के प्रति जागरूकता पैदा की जाएगी.

पर एकाएक यह चेतना आई कैसे? शायद इसके कई कारण हैं जो एक दूसरे से संबद्ध नहीं हैं. भारतीय शहरों को भी पश्चिमी रोग लग चुके हैं. जनसंख्या का बोझ बढ़ना, कुर्सी पर बैठे-बैठे काम करना, प्रतिद्वंद्विता के कारण तनाव बढ़ने से दिल का दौरा पड़ना, रक्त-चाप की समस्या, रक्त में कोलेस्टरोल बढ़ना वगैरह ऐसे ही 'रोग' हैं. जसलोक अस्पताल के एक हृदयरोग विशेषज्ञ बताते हैं, "इन्हीं कारणों से हर आदमी चौकन्ना हो गया है."

पार्टियों में खाने के पहले होने वाली बातचीत से भी बदलाव का पता चलता है. औरतें एक साथ बैठकर यही बतियाती हैं कि वजन घटाने या मोटापा कम करने के लिए वे कौन-सी किताब पढ़ रही हैं. और मर्द भी अब वेटर से सोडे में नींबू डालकर लाने को ही कहते हैं. आज मोटे होने की सामाजिक कीमत बहुत ज्यादा चुकानी पड़ती है. अब शादियों के बंधन भी उम्र भर के लिए नहीं होते. तंदुरुस्ती की एक जबरदस्त पैरोकार रमा बेस कहती हैं, "पहले कभी विवाह का बंधन जनम-जनम के लिए माना जाता रहा होगा. आज तो मर्दों को दूसरी औरतों तक पहुंचने की 'सुविधा' है."

दूसरी वजह यह हो सकती है कि अब संयुक्त परिवार टूट रहे हैं. और सिर्फ मियां-बीवी-बच्चों तक के सीमित परिवार होने लगे हैं. पति-पत्नी दोनों काम करते हैं. दोनों को न तो चैन है न सुकून, ऐसे में दादी अम्मा की राय मानने की कौन कहे. दिल्ली विश्व-विद्यालय की छात्रा शबनम सिंह कहती हैं, "हां मैं आजकल डायटिंग कर रही हूं. क्या हर व्यक्ति ऐसा नहीं करता?"

सौम्य भारतीय कपड़े भी अब इसी प्रवृत्ति के अनुरूप होने लगे हैं. एक गृहिणी विनय महाजन कहती हैं, "साड़ी में तो शरीर की हर खामी छिप जाती है. पर अगर सलवार कमीज पहननी है तो दुबला होना लाजिमी है." कई लोगों पर तो जैसे चुस्त-दुरुस्त होने की धुन सवार हो गई और जल्दी ही उन्हें पता चल गया कि इसके क्या फायदे हैं.

आम लोगों के आदर्श—राजनेता, खिलाड़ी और फिल्मी सितारे अब चुस्त-दुरुस्त रहने की कोशिश करते हैं. फिल्मों में अब मोटी कमर वाली हीरोइनें नहीं चल सकतीं जिन्हें कभी 'अच्छी खाती-पीती' मानकर बर्दाश्त कर लिया जाता था. सी-रॉक हेल्थ क्लब के प्रबंधक राजन प्रभु कहते हैं, "सटे-चिपके कपड़ों में हीरो और हीरोइन को दिखाए बिना कोई फिल्म आज पूरी नहीं होती."

यह नया उत्साह लाने में पश्चिमी प्रचार-तंत्र का भी कम हाथ नहीं रहा है. अमेरिकियों ने अपनी औसत जीवनावधि की संभाव्यता महत्वपूर्ण ढंग से बढ़ाकर सारी दुनिया का ध्यान आकृष्ट किया है. धीरे-धीरे दूरदर्शन पर भी इसका असर हुआ और उसने 'दस कदम' प्रसारित करना शुरू किया. दूर-दर्शन के एक अधिकारी बताते हैं, "हमारे पास ऐसे कार्यक्रम दिखाने का आग्रह करने वाली चिट्ठियों का ढेर जमा हो गया." दूरदर्शन के नए कार्यक्रमों में से एक—'बड़े लोगों' की चुस्ती-दुरुस्ती पर आधारित है. जबकि 'स्पोर्टसवीक' का संपादन संभालने के साथ ही सुनील गावसकर ने उसमें जीवन शैली से संबंधित एक नया स्तंभ शुरू कर

भारतीयों में तंदुरुस्त होने की ललक महत्वपूर्ण है. स्वस्थ लोग कार्यकुशल होते हैं, वे बेहतर काम करते हैं, बेहतर तरीके से जीते और खुशमिजाज रहते हैं

व्यायाम कक्षा का दृश्य (दाएं); और सुबह घूमने निकले लोग

भवान सिंह

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दिया है जो स्वास्थ्य पर केंद्रित है. अब तो महिलाओं की कोई भी पत्रिका मोटापा कम कराने के लिए आहार नियंत्रण वाली बातें छापे बिना पूरी ही नहीं हो सकती.

पर यह स्थिति आज बनी है. अभी हाल-हाल तक अपने यहां इन बातों पर कोई खास ध्यान नहीं देता था. आम भारतीय तो यही मानते थे कि शादी के बाद औरत के शरीर पर चर्बी चढ़ना और मर्द की तोंद निकल आना समृद्धि, अच्छा भोजन मिलने और सुखी वैवाहिक जीवन की निशानी है. देश में तंदुरुस्ती अभियान की अगुआ बनी वीना मर्चेंट कहती हैं, "भारतीयों के चेहरे कितने खूबसूरत हैं लेकिन शरीर का उन्होंने क्या कबाड़ा कर रखा है."

1982 में आकर तंदुरुस्ती की चिंता मूर्त रूप ले सकी. एशियाड हुआ और उसने जैसे सब कुछ बदल दिया. पहली बार लोगों ने पाया कि शरीर भी कितना खूबसूरत हो सकता है और उन्हें इस बात का भी एहसास हुआ कि भारतीय कुल मिलाकर बहुत स्वस्थ नहीं हैं. और इसी शर्म का परिणाम खेल प्राधिकरण के रूप में सामने आया जिसने स्वस्थ रहने का देशव्यापी प्रचार किया. इसके अंतर्गत 'रन फॉर फन', 'जोगाथंस', 'पे-ऐंड-प्ले' योजना तथा छोटी व्यायामशाला बनाने वाले को ब्याजमुक्त कर्ज देने की योजनाएं अमल में लाई गईं. अब सरकार से मिलते अच्छे वित्तीय समर्थन के बल पर प्राधिकरण यह काम पूरे देश भर में कर रहा है. प्राधिकरण के मेजर ओ.पी. भाटिया कहते हैं, "1990 तक इसका असर दिखने लगेगा."

तब यह बदलाव भले ही दिखने लगे पर अभी तक तो शरीर स्वस्थ रखने का एकमात्र उपाय योग ही था, जो है तो फायदेमंद पर बहुत ही उबाऊ है. ऐसे में स्वस्थ रहने के और तरीके सामने ही थे. तभी जेन फोंडा तथा उन्हीं के साथ इस क्षेत्र में फिल्म अभिनेत्री रेखा का पदार्पण हुआ. रेखा के 'माइंड ऐंड बॉडी टेंपल' की तो 75000 से ज्यादा डिस्क बिक चुकी हैं.

भारत में सबसे चमत्कारी बदलाव एरोबिक्स के रूप में हुआ है. ऐसी दूसरी कोई व्यायाम पद्धति नहीं. इसमें संगीत की तेज धुन पर उससे आगे निकलने की कोशिश की जाती है. यह शरीर को दुरुस्त करने के साथ दिल को भी दुरुस्त करने की पद्धति है. व्यायाम का स्तर ऊपर उठता जाता है तो उतनी तेजी आती जाती है.

47 वर्षीय वीना मर्चेंट एरोबिक्स को

रघु राय

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

व्यवस्थित ढंग से साल भर पहले दिल्ली में ले आई. आजकल वे छह जगहों पर काम देख रही हैं और उन्हें पटना, पानीपत और अमृतसर में भी ऐसे केंद्र शुरू करने का न्यौता मिल चुका है. बंबई के तलवलकर (जिनकी अब सात व्यायामशालाएं हैं) की प्रोग्राम डायरेक्टर आशा शेर्लेकर ने जब एरोबिक्स प्रशिक्षण देने वालों के लिए कार्यक्रम की घोषणा की तो उनके पास 80 आवेदन आ गए. एरोबिक्स लक्ष्य तय करके किया जाने वाला व्यायाम है. आप इससे महीने भर में पांच से 10 किलो वजन कम कर सकते हैं.

चंडीगढ़ में बेट्टी सलधाना ने नृत्य से जुड़ा कार्यक्रम बना रखा है जिससे 'तंदुरुस्ती कला और मनोरंजन की भी चीज बन जाती है और साथ ही व्यक्ति को इससे ऊब नहीं होती'. बंबई में 12 से 50 वर्ष तक की महिलाएं फरीदा पेडर के 'ला बांबा' में कैलिप्सो नृत्य करती हैं और यह धीरे-धीरे लोकप्रिय होता जा रहा है. पेडर कहती हैं, "नृत्य करने के बाद आपको थकावट नहीं बल्कि लगेगा कि नई ऊर्जा मिल गई है."

हेल्थ क्लबों का धंधा जबरदस्त तरीके से चल निकला है. एक साल में ही 'ताज पैलेस' ने अपने रेट प्रति जोड़े के लिए 3000 रुपए बढ़ा दिए. बंबई के 'सी-रॉक' की सदस्य संख्या 1981 के 15 के मुकाबले आज 900 हो गई है. प्रभु कहते हैं, "हमने तो अब वेटिंग लिस्ट भी बंद कर दी है." इसमें हर तरह के लोग सदस्य बनने लगे हैं. बंगलूर के एक कट्टरपंथी मुस्लिम परिवार की एक नौजवान लड़की रोज छिपकर व्यायामशाला में आती है. 38 वर्षीया आयशा खालिद कोई दिन नागा नहीं करतीं.

छोटी व्यायामशालाएं भी काफी बड़ी संख्या में हैं. बंबई में आज एक मील के दायरे में कोई न कोई व्यायामशाला मिल जाएगी जहां आप 15 रुपए महीने पर व्यायाम कर सकते हैं. 17 वर्षीय धोंडू सदाशिव रोज सुबह छह बजे व्यायामशाला पहुंच जाता है. वह प्रति मिनट 100 बैठक की आश्चर्यजनक रफ्तार से 200 बैठकें लगाता है और फिर 20 मिनट तक कुश्ती लड़ता है.

पर पैदल चलना और दौड़ना यानी जॉगिंग ही शायद सबसे ज्यादा लोकप्रिय है. विदेश जाकर लौटे भारतीय यह देखकर दंग रह जाते हैं कि विदेशों में वे अपने शरीर का कितना ख्याल रखते थे जबकि अपने यहां तो शरीर को जलेबियां और तंदूरी मुर्गे ठूंसने का बोरा मान लिया जाता है. नियमित रूप से दौड़ने वाले सुनील गुप्त कहते हैं, "दौड़ना तंदुरुस्त रहने और अपनी मुश्किलें दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका है." इससे आपको जिस बला से मुक्ति मिलती है, वह है शहरी जीवन से पैदा हुए तनाव."

रेसकोर्स में तो सवेरे घोड़े कभी-कभार ही दिखते हैं पर 5.30 बजे धुंध छंटने से पहले यहां 15 मील तक से पैदल या दौड़ते आए लोगों का मेला-सा लगा रहता है. इनमें साड़ी और स्नीकर पहने औरतें, कराटे प्रशिक्षक, गुजराती वेशभूषा वाली लड़कियां, 'पिता जी के कहने' पर आए बच्चे, शेयर बाजार की चर्चा करते कपड़ा व्यापारी और इसे संवाद का सबसे बढ़िया माध्यम मानकर निकले जोड़े भी शामिल होते हैं. पीरामल अस्पताल के स्पोर्ट्स मेडिसिन सेंटर की डॉ. स्वाति पीरामल कहती हैं, "चर्बी शारीरिक व्यवस्था पर एक बोझ है और व्यायाम उम्र न बढ़ने देने की दवा है." केंद्र 200 रुपए में पूरे शरीर की जांच का ब्यौरा दे देता है.

तंदुरुस्ती की धुन बढ़ने का असर यह हुआ है कि इससे संबंधित चीजों के कारोबार में वृद्धि हुई है. ट्रैक सूट, दौड़ने के जूते, चमकदार रंगों के बनियान-कच्छे, लेग वार्मर, रोईंग मशीनें, पांव चक्की इत्यादि का उत्पादन अब देश में ही होने लगा है. दिल्ली के पायनियर स्पोर्ट्स के चेतन सिंह कहते हैं, "अब लोग कलाई वाली पट्टी, सिर की पट्टी, मोजे और टोपियां तक खरीदते वक्त रंगों का मेल जरूर देख लेते हैं." हीरो साइकिल के एजेंट संजय पटेल बताते हैं कि अहमदाबाद में 'एक्सर-साइकिलें' दनादन बिक रही हैं और इस क्षेत्र की अपने यहां की सबसे प्रसिद्ध कंपनी 'बुलवर्कर' के देश भर में 600 एजेंट हैं.

लोग खाने-पीने की चीजों पर भी ध्यान देने लगे हैं. कई चीजें बदलने लगी हैं.

तंदुरुस्ती के इस जुनून का नतीजा है कि ट्रैक सूट, दौड़ने के जूते, मोटापा घटाने वाले खाद्य पदार्थ और स्वास्थ्य संबंधी उपकरण बनाने वालों का धंधा चल निकला है

व्यायामशाला में मांसपेशियों का परीक्षण (दाएं); मोटापा घटाने के उपकरणों व खाद्यों की प्रदर्शनी

भवान सिंह

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बेकरियों में ब्राउन ब्रेड, होटल में हल्का भोजन और पार्टियों में डायट बियर का चलन बढ़ गया है. भोजन पकाने में इस्तेमाल होने वाले कम नुकसानदेह तेलों में होड़ लग गई है. स्लिम एड और कैल-850 जैसे वैकल्पिक भोजन एकाएक बाजार में आ गए लगते हैं. आलू के चिप्स बनाने वाली एक कंपनी घोषणा करती है कि इसके पैकेटों में तेल का अंश 15 फीसदी कम है. आहार विशेषज्ञ कक्कड़ कहते हैं, "कुछ साल पहले तक तैयार मसालों का नाम भी नहीं था. वह दिन दूर नहीं जब बिना चीनी वाली चीजें बाजार में आ जाएंगी."

प्रमुख होटलों ने अपने प्रयोग शुरू भी कर दिए हैं. ताज ने 'छोटा ही खूबसूरत है' के आदर्श वाक्य से एक नया रेस्तरां 'मेनागे ए ट्रोइस' खोला. हॉलीडे इन ने समुद्र तट पर और आसपास दौड़ लगाने की सुविधा मुहैया कराने और कम कैलोरी वाला भोजन देने का नया कार्यक्रम शुरू किया.

खाने में भुनी और चुस्त-दुरुस्त रखने वाली चीजों का चलन बढ़ता जा रहा है. खाद्य विशेषज्ञ और स्तंभकार जे.एस कालरा कहते हैं, "सबसे अधिक बदलाव हमारे नाश्ते में आया है. अब पराठे नहीं चलते. साधारण घरों में भी ब्रेड, अंडे और पनीर का नाश्ता होने लगा है." उनके अनुसार कॉकटेल पार्टियों में खाने-पीने की सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है. शराब उतना नुकसान नहीं पहुंचाती जितना उसके साथ थोड़ी-थोड़ी करके खाई गई अंट-शंट चीजें. और जब तक खाना परोसा जाए तब तक खीरा बनने गया आदमी भी पसरकर कद्दू बन गया होता है. 13 महीनों में 26 किलो वजन खोकर कालरा ने इस बला से सिर्फ अपनी इच्छाशक्ति से विजय हासिल की. वे कहते हैं,"अब मुझ में बहुत ऊर्जा बची लगती है. दिन भर खूब काम करता हूं और बिस्तर में लेटते ही सब कुछ भूल जाता हूं."

तंदुरुस्ती अब सेहत के हिसाब से नापी जाती है, दुबलेपन से नहीं. जानी-मानी सौंदर्य विशेषज्ञ शहनाज हुसैन कहती हैं, "यह सिर्फ बीमारी से मुक्ति ही नहीं बल्कि जीवन-शक्ति से भरपूर होना भी है. मुझे देखिए, मैं तो हरदम रेस में दौड़ने को तैयार घोड़े जितनी ऊर्जा महसूस करती हूं." ठंडा पानी प्रमुख पेय बन गया है. लोग अपने बच्चों के टिफिन बाक्स में एकाध फल रखने लगे हैं. कालरा बताते हैं, "बाहर खाने वाले लोगों में से 70 फीसदी अपने शरीर पर ध्यान देते हैं. और

भवान सिंह

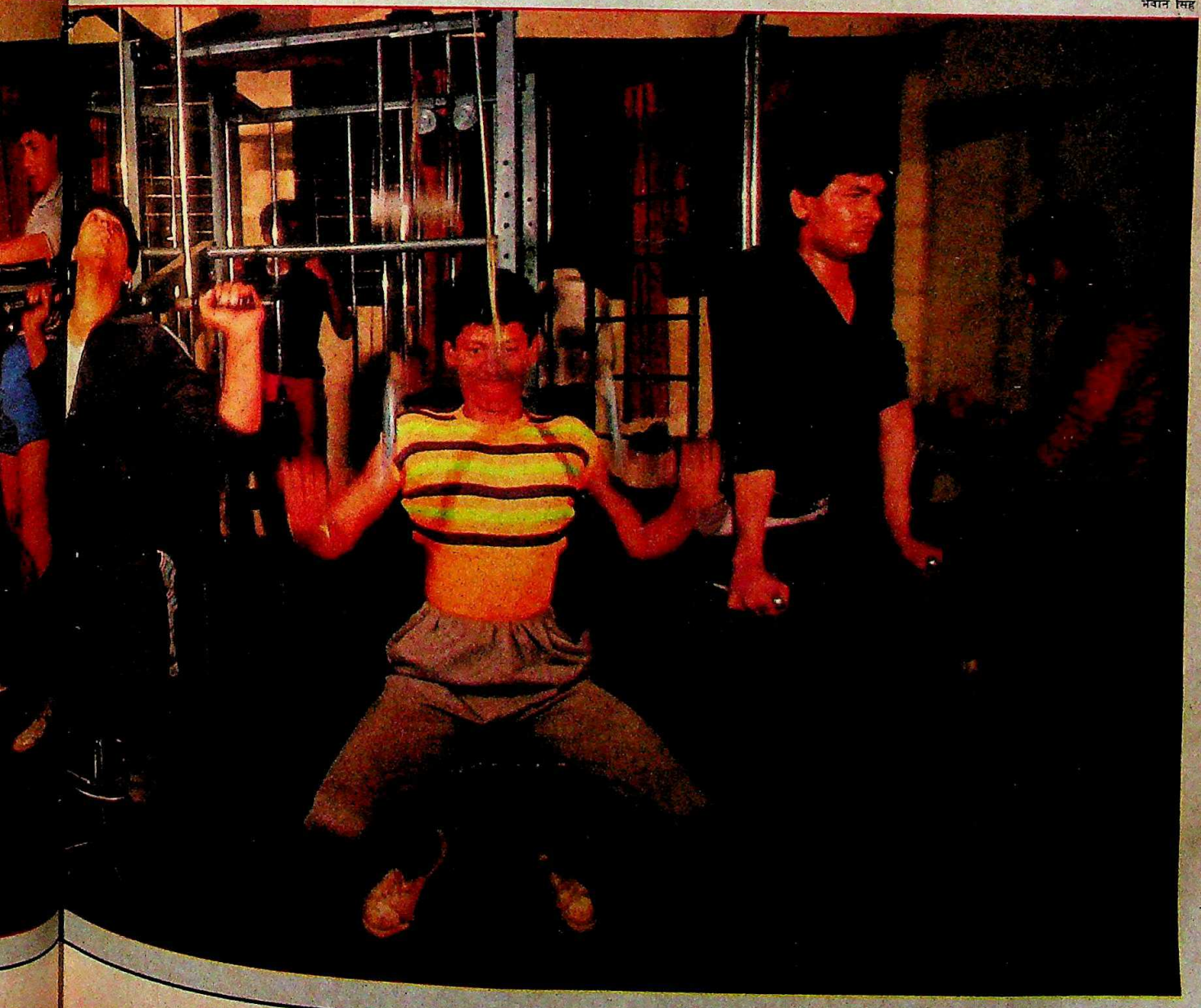

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

महिलाओं में शायद ही कोई ऐसी मिले जो डायटिंग नहीं करती.'' कैलोरी का हिसाब लगाते-लगाते कई महिलाएं गणितज्ञ हो गई हैं. उनको पता है कि टोस्ट में 50 कैलोरी, उबले अंडे में 80 कैलोरी और गुलाब जामुन में असंख्य कैलोरी ऊर्जा होती है. पर आहार विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ कैलोरी गिनने से काम नहीं चलने वाला. खूबसूरत शरीर के लिए संतुलन जरूरी है: कैलोरी कम करें, व्यायाम बढ़ाएं.

इस काम में भी बढ़िया कमाई का मौका देखकर अनेक ब्यूटी पार्लरों ने मोटापा घटाने का धंधा भी शुरू कर दिया और नाम रख लिया 'कर्ल्स ऐंड कर्व्स', 'फिगर ऐंड फेस', 'स्लिम ऐंड शेप'. निजी आहार विशेषज्ञों ने हर आदमी की शरीर रचना के आधार पर उसका आहार तय करना शुरू किया.

इसी दौरान आयुर्वेदिक और प्राकृतिक दवाखानों का जोर भी बढ़ा है. केरल में ही ऐसे 100 से अधिक क्लिनिक हैं. आयुर्वेद के अनुसार मोटे आदमी में काफी वसा जमा हो जाता है. इसका इलाज जड़ी-बूटियों से पाचन क्रिया को तेज करना है. कई लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा से भी लाभ होता है. यह सुरक्षित और सस्ता (पूरा कोर्स 200 रुपए) है और इसमें प्रति हफ्ते औसतन तीन से चार किलो वजन कम हो जाता है. दौलतराम केंद्र के डॉ. एन.के. शर्मा कहते हैं, ''हमारी सफलता इसी संदेश में छिपी है कि पेट भर खाओ पर सही चीजें खाओ.'' सही चीजों में सलाद, फल, अंकुरित अनाज और भीगे हुए बादाम-मूंगफली वगैरह आते हैं.

पर डायटिंग के बारे में एक बात पक्की है कि जरूरतमंद कुछ भी करने को तैयार रहते हैं. दिल्ली के ताज हेल्थ क्लब की मैनेजर देवकी श्रीनिवास कहती हैं, ''आपकी जीवन पद्धति में बदलाव होना तय है. लेकिन यह काम लोग खुद नहीं कर सकते इसलिए सलाह-मशविरा देने वालों का धंधा चलता रहता है.'' इसी में 'शेरी लुई' और 'बॉडी रैप' जैसी संस्थाएं भी आती हैं. 'शेरी लुई' ने तो बड़े जोर-शोर से धंधा शुरू किया पर अंत में टांय-टांय फिस्स साबित हुई. देश भर में खुले इसके केंद्रों में मोटापे से परेशान लोग भीड़ लगाए रहते थे. इसके एक पुराने ग्राहक ने बताया, ''मुद्दा यह नहीं कि शेरी लुई बंद हो गई. बल्कि इसने तंदुरुस्ती के प्रति लोगों की बढ़ती ललक को उजागर किया.''

'बॉडी रैप' ने और भी आश्चर्यजनक परिणामों का दावा किया: अगर 60 मिनट का समय दे सकते हों तो एकदम नया शरीर पाइए. इसके प्रमुख नरेंद्र गोराडिया अब देशभर में फैले 12 केंद्रों के मालिक हैं. दिल्ली की 'कर्ल्स ऐंड कर्व्स' ने एक ऐसी मशीन मंगाई है जिसके बारे में दावा किया जाता है कि घंटे भर के अंदर पेट को कई इंच कम कर सकती है. डॉ. कक्कड़ स्वीडन से ऐसी मशीन मंगाने की सोच रहे हैं जो मोटे लोगों के शरीर के अंदर 'इंट्रागैस्ट्रिक बैलून' पहुंचा देगी जिससे उस आदमी को तीन महीनों तक अपना शरीर भरा-भरा लगेगा.

इस सब पर काफी पैसा लगता है. पर अच्छा शरीर भी सस्ते में नहीं बन जाता. शरीर में बैलून पहुंचाने में करीब 15000 रुपए खर्च होते हैं. चार महीने पहले भोपाल में खुले एक बहुत ही सफल आहार क्लिनिक 'स्लिम फास्ट' में 15 किलो वजन कम करने के 4,900 रुपए लिए जाते हैं. 'कर्ल्स ऐंड कर्व्स' में एक बैठक की फीस 125 रुपए है.

आखिर अलग-अलग लोग अपनी तंदुरुस्ती के लिए अपना ही कार्यक्रम तैयार कर लेते हैं जो उनकी जीवन शैली, क्षमता और जेब के अनुरूप होता है. फोटोग्राफर सैम मैथ्यू रोज सुबह जमकर बागवानी करते हैं. जयपुर की गृहिणी दीपा भाटिया ने बच्चा होने के बाद अपनी नौकरानी को हटा दिया और घर के सारे काम करने लगीं. सारे देश में चक्कर काटते रहने वाले चार्टर्ड एकाउंटेंट एस.पी. सूरी हवाई अड्डों पर विमान की प्रतीक्षा करते समय ही सुबह की अपनी सैर का कोटा पूरा कर लेते हैं. और स्कूल के दिनों में भोजनभट्ट रहे उदय चंदर अब इस आदत से पिंड छुड़ा चुके हैं. वे कहते हैं, ''मैं सपने में भी कहीं न कहीं कैलोरी का हिसाब जोड़ रहा होता हूं.''

पर अभी भी यह सब रफ्तार नहीं पकड़ पाया है. हुसैन कहती हैं, ''जब मुश्किलें शुरू

दौड़ लगाना शहरियों के तनाव को घटाने का सबसे बढ़िया उपाय है

गणतंत्र दिवस परेड में खिलाड़ी (दाएं); एरोबिक्स करते लोग (नीचे); और योगाभ्यास

भवान सिंह

भवान सिंह

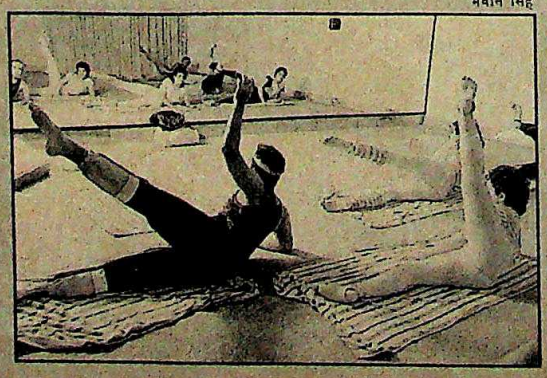

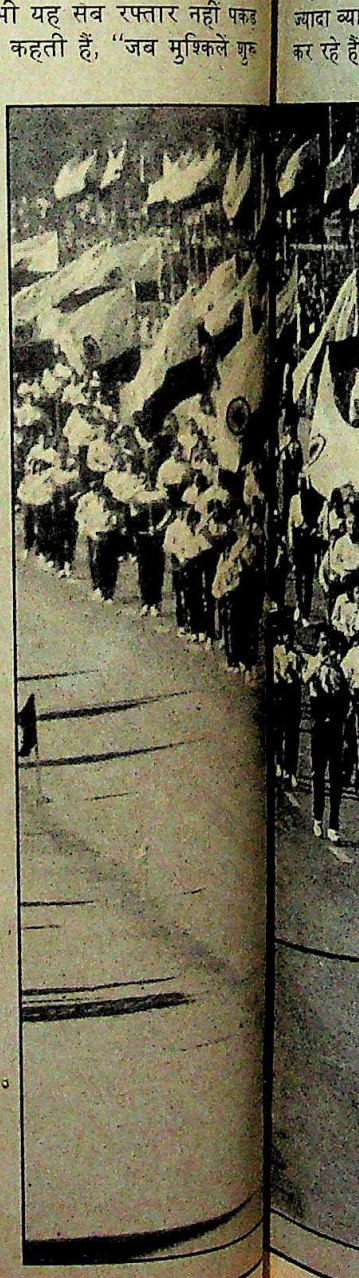

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

होती हैं तभी जाकर भारतीय औरतों की नींद खुलती है. और फिर वे इसे ओलंपिक की तैयारी वाले अंदाज में लेती हैं." तेजी से मोटापा घटाने के चक्कर में कुछ खतरे भी हैं. इससे बाल गिरना, आंखों के आगे अंधेरा छाना, झुर्रियां पड़ना, अरुचि या ज्यादा खा लेने के रोग हो सकते हैं. इससे भी बुरी बात यह कि जीवन के प्रति निराशा भी आ सकती है. अच्छा आहार है: सब कुछ में से थोड़ा खाना, किसी भी एक चीज की अति न करना.

इसी तरह व्यायामों में शुरुआत और उन्हें समाप्त करने के पहले की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है. प्रसिद्ध आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन डॉ. स्टुअर्ट स्प्रिंगर, जो हाल ही में भारत आए थे, कहते हैं, "दर्द होने का मतलब है कि आप ज्यादा व्यायाम कर रहे हैं या गलत तरीके से कर रहे हैं." इससे आप घायल हो सकते हैं, आपकी कोशिकाएं टूट सकती हैं और मोच तक आ सकती है. व्यायाम हौले से शुरू करके धीरे-धीरे बढ़ाते जाना चाहिए.

लेकिन चाहे जो हो, तंदुरुस्ती के मामले में भारत अभी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कहीं नहीं ठहरता. अधिकांश लोगों को स्वास्थ्यकर भोजन के बारे में कुछ पता नहीं है. खेल की सुविधाएं कम हैं. और तो और, पत्रकार राहुल बेदी जैसे लोगों को "खेल के क्लबों में किसी सदस्य का मेहमान बनकर घुसना पड़ता है." सबसे सस्ते व्यायाम, जॉगिंग के लिए नई जगहें बची नहीं रही हैं और दौडने के जूते यहां नहीं बनते. फरीदा पेडर कहती हैं, "दौड़ते समय आपको मैनहोल में गिरने, बस-कार से कुचले जाने या कबाड़ में गिर पड़ने का खतरा बना ही रहता है." खेल प्राधिकरण के मेजर भाटिया भी मानते हैं कि सुविधाएं सीमित हैं, "हमें हजार गुना ज्यादा सुविधाओं की जरूरत है."

इस बीच यह देख लेना उपयोगी होगा कि आप कितने तंदुरुस्त है. क्या आप बस पकड़ने के लिए दौड़ सकते हैं? दिन भर काम करने के बाद आपको कैसा महसूस होता है? आईना देखने पर क्या आप संतुष्ट हो जाते हैं? क्या आप बहुत जल्दी बेचैन हो जाते हैं? बिना सांस फूले क्या आप सीढ़ियों से तीन मंजिल तक जा सकते हैं? क्या पेट के पास चुटकी से पकड़ने पर एक इंच से मोटी चमड़ी आती है? आपको नींद कैसी आती है? अगर इनके जवाब गड़बड़ आते हैं तो कल सुबह ही उठकर घर से बाहर निकलिए. वहां कई लोग आपके साथी बनने के लिए तैयार दौड़ रहे हैं.

—**सिमरन भार्गव, सलिल त्रिपाठी और ब्यूरो रिपोर्ट**

प्रशांत पंजियार

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

जगबीती
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रधानमंत्री का दौरा

स्वीडन के किस्से

इस बार राजीव गांधी ने बोफोर्स की जन्मभूमि स्वीडन का रुख किया. मौका था छह देशों का शिखर सम्मेलन. स्टॉकहोम में उनकी मौजूदगी के दौरान ही वहां के सरकारी वकील ने बोफोर्स सौदे में रिश्वत लिए जाने के मामले में कुछ नए रहस्योदघाटन करके पूरे कांड को एक नया मोड़ दे दिया. लेकिन विदेश यात्राओं में पत्रकारों से खुलकर बातचीत करने के अपने पुराने अंदाज को छोड़ इस बार राजीव चुप्पी साधे रहे. उनके विमान में साथ गए वरिष्ठ संपादक प्रभु चावला ने इस यात्रा का यह शब्दचित्र खींचा:

राजीव गांधी के लिए सबसे गर्वीले और प्रभावशाली क्षण वे होते हैं जब अपनी किसी विदेश यात्रा के दौरान वे विदेशी पत्रकारों के सामने अपने आकर्षक व्यक्तित्व और हाजिर जवाबी का प्रदर्शन करते हैं. लेकिन इस बार शिखर सम्मेलन के लिए स्वीडन यात्रा के दौरान वे संवाददाताओं से लगातार बचते रहे.

इस रवैये से इस शक को बल मिलना स्वाभाविक ही था कि राजीव बोफोर्स मामले पर होने वाली खिंचाई से कतरा रहे हैं. उधर सरकारी वकील लार्स रिंगबर्ग के इस बयान से कि वे बोफोर्स रिश्वत कांड की जांच का काम कुछ हद तक इस वजह से बंद कर रहे हैं कि भारत सरकार का रवैया असहयोगपूर्ण रहा है, मामला और सरगर्म हो उठा.

प्रभु चावला

राजीव के साथ चलने वाले अधिकारियों की दलील थी कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम इतना व्यस्त है कि उसमें पत्रकारों के लिए समय निकाल पाना नामुमकिन है. उनकी दूसरी दलील थी कि बोफोर्स के मामले में सवालों के जवाब देने का मतलब संसदीय नियमों का उल्लंघन करना होगा क्योंकि इस समय एक संसदीय समिति मामले की जांच कर रही है. शारदा प्रसाद की दलील थी, "शिखर सम्मेलन में आए किसी भी दूसरे नेता ने प्रेस से अकेले बातचीत नहीं की. इसलिए ऐसी बातचीत करना हमारे लिए उचित नहीं होगा."

सीधी-सी बात है कि राजीव के अति सतर्क 'चाणक्य', खास तौर से उनके दून स्कूल वाले यार लोग, अपने बॉस को बोफोर्स कांड से जुड़े सवालों के गोलों के आगे खड़ा करने का खतरा मोल लेने को तैयार नहीं थे. इस बार तो स्वीडिश प्रधानमंत्री इंगवार कार्लसन ने भी बोफोर्स से जुड़े सवालों से उनकी रक्षा करने की जिम्मेददारी बखूबी निभाई. संयुक्त प्रेस सम्मेलन में तो उन्होंने एक सवाल के जवाब में तपाक से कहा कि, "आप गलत प्रेस सम्मेलन में आए हैं."

प्रधानमंत्री के साथ उनके चार्टर्ड विमान में तैनात अफसरों के लिए यह यात्रा किसी हवाई पांच सितारा होटल में उड़ान भरने या फिर हवाई क्रिसमस पार्टी में तोहफे इकट्ठे करने जैसी होती है. इन मौकों पर एअर-इंडिया का महाराजा पानी उसका अमला प्रधानमंत्री के सहयात्रियों पर जी भरकर रूसी कैविआर, स्वीडिश चॉकलेट और आयातित स्कॉच तथा शराब की बोतलों के उपहार लुटाता है.

पर इस बार महाराजा ने भी विशुद्ध समाजवादी चोला पहन लिया. न तो साथ ले जाने के लिए इस बार कैविआर की व्यवस्था थी और न स्कॉच ह्विस्की की. भेंट के रूप में दिए जाने वाले झोलों में इस बार आफ्टर-शेव लोशन की छोटी-छोटी शीशियों के अलावा सिर्फ कंघे थे जिन पर एअर-इंडिया का चिन्ह अंकित रहता है. प्रधानमंत्री से लेकर यात्री दल के दो चपरासियों तक सभी के खाने की सूची भी एक जैसी थी: छह व्यंजनों वाले इस भोजन में कबाब, जंबो झींगा, खुंबी, एपल-पाई, गुलाबजामुन और चॉकलेट. इसके अलावा दारू मुफ्त थी.

न केवल सुमन दुबे और गोपी अरोड़ा (बाएं), बल्कि स्वीडिश प्रधानमंत्री कार्लसन (नीचे) ने भी राजीव का बचाव किया

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पीआइडी

प्रभु चावला

स्वीडन ने एकमुश्त सौदे की पेशकश की लेकिन राजीव ने इसे नजरंदाज कर दिया. इस बीच सोनिया लोगों से मेलजोल में लगी रहीं

सोने पर सुहागा यह रहा कि आमतौर पर प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं के दौरान भारतीय दूतावासों द्वारा प्रधानमंत्री के दल के साथ जाने वाले पत्रकारों को मुहैया कराई जाने वाली महंगी स्कॉच शराब भी इस बार नदारद थी. भारतीय दूतावास ने इस बार सर्द दूरी बनाए रखी. प्रधानमंत्री के दफ्तर ने बता दिया था कि भारतीय मुसाफिरों को अपना खर्च खुद ही उठाना होगा क्योंकि यहां से 5000 मील दूर बसा सूबे से पीड़ित देश उनका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकेगा.

भारतीय और स्वीडिश प्रधानमंत्रियों ने शिखर सम्मेलन की बैठक के अलावा आधे घंटे तक अकेले में भी बातचीत की. इस बैठक के बाद मेजबानों को कुछ नाटकीय घोषणाओं की उम्मीद थी. लेकिन सरकारी घोषणा नीरस और पूर्वानुमानित रही. सरकारी ब्यौरे के अनुसार दोनों नेता एक दूसरे के विचारों से सहमत ही हुए. प्रेक्षकों को आश्चर्य हुआ कि इस बैठक से कुछ सक्रिय और ठोस क्यों नहीं निकला. आखिरकार दोनों देशों के बीच व्यापार माचिस के बक्से बनाने से लेकर तोपें बनाने तक के विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है. भारत द्वारा स्वीडन से गैर-सुरक्षा माल को 1983-84 में 115 करोड़ रुपए का आयात 1986-87 में बढ़कर 350 करोड़ रुपए हो चुका है. अफवाह ऐसी थी कि कोई जोरदार सौदा होने जा रहा है पर भारत इसमें से खिसक गया. स्वीडन ने भारत को 1000 करोड़ रुपए के छोटे टैंक और वायुसेना के लिए, यंत्र बिजली परियोजनाओं के लिए 150 करोड़ रुपए का अनुदान और एक अत्याधुनिक संचार व्यवस्था देने की पेशकश की थी और वह भी इतनी आसान शर्तों पर कि सहसा विश्वास नहीं होता. लेकिन राजीव ने इस मामले को यह कहकर टाल दिया कि भारत सरकार इस एकमुश्त पेशकश पर बाद में विचार करेगी.

राजीव के साथ उनकी पत्नी और दो बच्चों के अलावा सुरक्षा कर्मियोंसहित करीब 50 अफसर थे. उनके साथ गए प्रतिनिधि-मंडल में दो राज्यमंत्रियों नटवर सिंह, और एदुआर्दो फेलिरो और उनके सचिव स्तर के तीन अफसर, विदेश सचिव के.पी.एस. मेनन, सूचना सलाहकार एच.वाई. शारदा प्रसाद, सूचना और प्रसारण सचिव गोपी अरोड़ा और पर्यावरण सचिव टी. शेषन के अलावा तीन अतिरिक्त सचिव, चार संयुक्त सचिव और एक निदेशक शामिल थे. इन सभी लोगों ने स्टॉकहोम के सबसे महंगे होटल ग्रांड में 35 कमरों पर कब्जा जमाया. हर कमरे का दैनिक किराया 175 (2275) डॉलर या इससे अधिक था.

लेकिन इन सभी लोगों को इस यात्रा के दौरान करने के लिए कोई-न-कोई काम भी मिल गया. जहां नटवर सिंह को स्वीडन के सरकारी नेताओं को कंबोडिया के पदच्युत राजकुमार नरोत्तम सिंहनुक से अपनी बैठक का ब्यौरा देना था, वहीं फ़ेलिरो की मौजूदगी को यूरोपीय मामलों संबंधी उनकी जिम्मेदारी को देखते हुए जायज ठहराया गया. चार अधिकारियों शारदा प्रसाद, सुमन दुबे, मणिशंकर अय्यर और गोपी अरोड़ा-गुट के जिम्मे प्रधानमंत्री के भाषण तैयार करने और छोटे वक्तव्यों को मसालेदार बनाने का काम था. इसके बावजूद कई अधिकारियों का काम तो बस सुंदर दृश्यों को निहारना भर था.

सोनिया, राहुल और प्रियंका स्टॉकहोम में सैर-सपाटे कर रहे थे. सोनिया रेशमी साड़ी पहने घूम रही थीं तो बच्चे जींस में. वे संग्रहालय और कला केंद्र देखने गए और भीड़ में खुलकर घुलते-मिलते रहे. कभी न मुस्कारने के लिए विख्यात सोनिया गांधी अपने शुभचिंतकों को देखकर मुस्करा रही थीं. बल्कि एक अफवाह तो यह थी कि वे हंसी भी. वे एक अस्पताल, आधुनिक कला के एक संग्रहालय और एक टेक्सटाइल कला केंद्र देखने गईं. इसके अलावा उन्होंने श्रीमती कार्लसन के साथ स्टॉकहोम के दो सबसे विशिष्ट रेस्तरांओं में दिन और रात का भोजन किया. उधर दोनों बच्चे राहुल और प्रियंका भी राजीव के व्यक्तिगत सचिव विंसेंट जॉर्ज के साथ स्टॉकहोम के पुराने इलाके में सैर-सपाटा करते रहे.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ब्रिटेन

प्रेस पर कसता शिकंजा

राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर थैचर सरकार सेंसरशिप सख्त कर रही है

मार्गरेट थैचर सरकार ने जिस तरह से अखबारों-पत्रिकाओं और रेडियो-टीवी पर लगातार हमले शुरू किए हैं उससे ब्रिटेन में प्रेस की आजादी के दावे की पोल खुल गई है. पिछले साल सरकार ने समाचार माध्यम के लोगों के खिलाफ जिस हिसाब से मुकदमे दायर किए हैं उससे प्रेस की आजादी को बड़ा धक्का लगा है.

समाचार पत्र उद्योग से वित्तीय सहायता प्राप्त प्रेस कौंसिल ने अखबारों-पत्रिकाओं के खिलाफ चलने वाले नौ मामलों का पता लगाया है. कौंसिल के निदेशक केनेथ मोर्गन के अनुसार, "इन सबसे ब्रिटेन उन देशों की मंडली में शामिल होता जा रहा है जहां प्रेस की आजादी की रक्षा की बात बेमानी होकर रह गई है." 'न्यू स्टेट्समैन के खोजी संवाददाता डंकन कैंपबेल के फ्लैट पर ब्रिटिश पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने छापा मारा और वहां से वे टेप उठा ले गई जो बीबीसी के 'सीक्रेट सोसायटी' कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले थे. इसमें 'जिरकोन स्पाइ सेटेलाइट' के काम का विश्लेषण किया गया था.

प्रेस पर हुए इस अपूर्व हमले से संपादक हिल गए हैं. उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वह सदियों से चल रही न्यायपालिका की आजादी को समाप्त करने की कोशिश कर रही है. उनका कहना था कि कई न्यायिक उद्घोषणाओं के कारण नया गोपनीयता कानून, फौजदारी कानून से ज्यादा शक्तिशाली और त्रासदायक बन गया है.

इस प्रकरण के मुख्य शिकार कैंपबेल ने 'न्यू स्टेट्समैन' में अपने नए लेख में लिखा है, "संसद में बीबीसी के सीक्रेट सोसायटी कार्यक्रम में जिरकोन का जिक्र करना ब्रिटेन के नए इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग उपग्रह कार्यक्रम का 'भंडाफोड़' करना नहीं था." लेख में कहा गया है कि इसका उद्देश्य इस बात को उजागर करना था कि उपग्रह पर खर्च की गई 50 करोड़ पाउंड की रकम का ब्यौरा संसद और लोक लेखा समिति से छिपाकर रखा गया.

अपने को 'पिको जर्नलिस्ट' कहने वाले कैंपबेल सरीखे खोजी पत्रकार इस बात से सख्त खफा हैं कि ब्रिटेन के विपक्षी दल, खासकर लेबर पार्टी के नेता नील किनॉक राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मसलों पर सशक्त विपक्ष की भूमिका अदा करने में सरासर नाकाम रहे हैं.

अगर 'जिरकोन स्पाइ सेटेलाइट' विवाद ने नागरिक अधिकार के लिए लड़ रहे लोगों

प्रेस का आरोप है कि कई न्यायिक उद्घोषणाओं के कारण नया गोपनीयता कानून फौजदारी कानून से ज्यादा शक्तिशाली और त्रासदायक बन गया है

के मन में डर पैदा किया है तो चर्चित 'स्पाइकैचर' प्रकरण के कारण टोरी सरकार उपहास का पात्र भी बन गई है. सरकार ने इस मामले में अखबारों के खिलाफ अदालत से निषेधाज्ञा हासिल कर ली है. साथ ही थैचर सरकार ने आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका में भी ऐसे मुकदमे कर रखे हैं. दरअसल ब्रिटिश सुरक्षा सेवा के पूर्व गुप्तचर पीटर राइट द्वारा उद्घाटित तथ्यों में कुछ खास आपत्तिजनक था भी नहीं. लेकिन 'गार्डियन', 'इंडिपेंडेंट' और 'आब्जर्वर' जैसे अखबारों ने राइट के आरोपों को बड़ी प्रमुखता से छापा. राइट का आरोप था कि कुछ धूर्त गुप्तचर लंदन स्थित विदेशी दूतावासों में बैठकर लेबर पार्टी के तत्कालीन प्रधानमंत्री हेरॉल्ड विल्सन का तख्ता पलटने का षड्यंत्र रचते रहते थे.

थैचर सरकार के इस कठोर रुख से और कुछ हुआ हो या नहीं, राइट के दिए ये ब्यौरे दुनिया भर में खूब बिके. और यह अखबारों के लिए साल का सबसे बढ़िया मुद्दा साबित हुआ. 'टाइम्स' ने जनसंपर्क का पुरस्कार मार्गरेट थैचर और उनके 'क्लाएंट' 'स्पाइकैचर' को देने की घोषणा भी की. पीटर राइट और उनके 'क्लाएंट' 'एम-16' को उपविजेता करार दिया गया.

अगर इस प्रसंग पर सरकार इतना बखेड़ा नहीं खड़ा करती तो लोग इसे हल्के तौर पर ही लेकर बिसार देते. लेकिन जैसा कि 'इंडेक्स ऑफ सेंसरशिप' के संपादक जॉर्ज थिनर मानते हैं कि अभी ब्रिटेन 'पश्चिमी दुनिया में सबसे संवेदनशील' देशों में से एक माना जाता है. उनकी पत्रिका में ईरान और तीसरी दुनिया में पत्रकारों के अधिकारों के हनन संबंधी कई लेख पढ़े रहते थे. अब ब्रिटेन भी इसमें काफी जगह घेरने लगा है.

पर क्या थैचर सरकार ने इससे कोई सबक नहीं सीखा है? ऐसा लगता तो नहीं. पिछले पखवाड़े सरकार ने पत्रकारों द्वारा सुरक्षा सेवाओं संबंधी जानकारियां प्रकाशित करने पर रोक लगाने के लिए एक अदालती लड़ाई शुरू की. सरकार ने एक और अखबार में एक नई किताब 'इनसाइड इंटेलीजेंस' का हिस्सा छापने पर रोक लगाने की निषेधाज्ञा अदालत से हासिल कर ली है. इस किताब के लेखक हैं 'एम-16' के सदस्य एंथनी कैवेंडिश. सरकार की इस कार्रवाई से संपादक लोग भुनभुनाते ही रह गए. अब उन्होंने 'डी-नोटिस कमेटी' को ही पूरी तरह छोड़ देने का फैसला कर लिया है.

यह संगठन पिछले 75 सालों से काम कर रहा है. यह प्रेस को देश की सुरक्षा से संबंधित उलटी-सीधी चीजें छापने से रोकने के लिए बना स्वयंसेवी संगठन है. वैसे किसी अखबार, पत्रिका या रेडियो-टीवी पर कुछ छपने या प्रसारित होने से रोक देने का कोई अधिकार इसे नहीं है. वह आठ मुद्दों की सूची समाचार माध्यमों के दफ्तरों को भेजता है जिनसे संबंधित मामले छापना राष्ट्रीय सुर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

SUNDAY TELEGRAPH

INSIDE

Thatcher likely to back Bill to cut

SEX IN THE 1990s

THE PRIME OF FAYE DUNAWAY

bazaar

CHRISTMAS BOOKS AND RECORD GUIDE

OBSERVER

AN ETHIOPIAN CHILD GELDOF WILL NOT SEE

C4 cash for Belgrano film

THE OBSERVER

REVIEW

One of the most pungent and diverting intellects ever to have emerged from the British Empire was 90 last week. IAN JACK celebrates the remarkable Nirad C. Chaudhuri and his new autobiography. Picture by ROGER HUTCHINGS.

THE TIMES

Rebel Tories defy Thatcher

Season's first catch of the Tay

Paper's victory on

THE INDEPENDENT

NEWSPAPER OF THE YEAR AWARD

SUMMARY

Kuwait may

Dramatic evidence of virus spread emerges from blood tests after all births in NY state

One in 61 New York

Risk facing

'इंडिपेंडेंट' के जेरेमी वार्नर को सजा हो गई तो यह फैसला ऐतिहासिक होगा, क्योंकि पिछले 25 वर्षों में यहां किसी पत्रकार को सूचना स्रोत छिपाने के आरोप में सजा नहीं हुई. यह प्रेस की आजादी के ताबूत में आखिरी कील भी होगी

के लिए ठीक नहीं माना जाता. वैसे इसे मानना या न मानना संपादक की मर्जी पर होता है. यह व्यवस्था दोनों पक्षों के आपसी व्यवहार पर चलती है. पर 'इंडिपेंडेंट' के आर्थिक मामलों के पत्रकार जेरेमी वार्नर के मामले में जो कुछ हुआ उससे संपादकों द्वारा 'सद्भावना के आधार पर चलने वाली इस व्यवस्था' को अंगूठा दिखाना जायज लगता है. वार्नर ने व्यापार और उद्योग विभाग के बड़े अधिकारियों द्वारा किए जा रहे घोटाले के संबंध में एक खबर दी थी. पर इस खबर का स्रोत स्कॉटलैंड यार्ड के गुप्तचरों को न बताने के कारण उनके सामने अब सजा भुगतने की नौबत आ गई है. देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था 'लॉ लार्ड्स' द्वारा अपील ठुकरा देने के बाद वार्नर को दो साल की सजा या जुर्माना या दोनों ही हो सकते हैं. यह कार्रवाई अदालत की मानहानि के 1981 के कानून के तहत की जाएगी.

यह मामला जल्दी ही हाइकोर्ट के सामने आने वाला है. मीडिया के विशेषज्ञों के अनुसार अगर वार्नर को सजा हो जाती है तो यह फैसला ऐतिहासिक होगा क्योंकि पिछले 25 वर्षों में किसी भी ब्रिटिश पत्रकार को सूचना स्रोत छिपाने के आरोप में सजा नहीं हुई है. साथ ही यह प्रेस की आजादी के ताबूत में आखिरी कील भी साबित होगी.

बीबीसी रेडियो-4 के कार्यक्रम 'माइ कंट्री राइट ऐंड रांग' नामक कार्यक्रम को भी लेकर सरकार और प्रेस के बीच ठनी हुई है. एकाध कानूनी पचड़ा भी चल रहा है. इस कार्यक्रम में भी सुरक्षा सेवा की भूमिका को टटोला गया है. इसी तरह चैनल-4 पर बर्मिंघम के शराब घर पर बमबारी वाली घटना को नाटकीय रूप में पेश करने पर भी रोक लगा दी गई है. प्रेस इन हमलों को किसी तरह झेल रहा है और सरकारी गोपनीयता कानून में होने वाले संशोधनों की प्रतीक्षा कर रहा है. पर सबसे आश्चर्य की बात है—इस मुद्दे पर जनता में कोई सुगबुगाहट न होना, संसद या सार्वजनिक मंचों या फिर अखबारों में भी वार्नर की परेशानी, स्पाइकैचर वाले मामले या प्रेस की आजादी के मुद्दे पर कोई खास बहस नहीं चल रही है.

ब्रिटिश कानूनों से जिन मुद्दों पर प्रेस की आजादी को खतरा है उन पर एक विधेयक लाने की सिफारिश करने वाले लॉर्ड स्कारमैन ने हाल में ही कहा है कि ब्रिटेन के लोग प्रेस को वैसा विशेष दर्जा नहीं देते जैसा अमेरिकी लोग देते हैं. उन्होंने कहा, "अगर उन्हें बेलगाम संसद और बेलगाम प्रेस में से एक को चुनना हो तो वे बेलगाम संसद को ही चुनेंगे."

बीबीसी ने जब कुछ दर्शकों को अपने अधिकारियों से सवाल करने के लिए आमंत्रित किया तो बहुत कम ही लोगों ने जिरकोन मामले या स्पाइकैचर या 'माइ कंट्री राइट ऐंड रांग' वगैरह के मामले में चिंता जताई. अपनी ओर से बीबीसी के अध्यक्ष मारमाड्यूक हसी ने जरूर कहा कि सरकार का बार-बार अदालत पहुंचना प्रेस की आजादी के लिए एक गंभीर खतरा है. लेकिन लोगों की दिलचस्पी उस बड़ी राशि को ही जानने में अधिक दिखी जो बीबीसी अपने बड़े टीवी सितारों को देती है.

थैचर ने इस शताब्दी में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहकर हरबर्ट हेनरी एस्क्विथ को भी पीछे छोड़ दिया है. लोगों के मन में नागरिक अधिकारों की जगह उद्योग-धंधों के मुद्दों के प्रति ज्यादा चिंता जगाना थैचरवाद की एक नई उपलब्धि है.

—रमेश चंद्रन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

श्रीलंका

जयवर्द्धने की घेराबंदी

भारतीय शांति सेना की मौजूदगी से श्रीलंका में नाराजगी बढ़ी

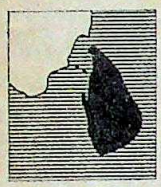

शायद इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती थी कि पिछले पखवाड़े श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्द्धने ने भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया. श्रीलंका में भारत-श्रीलंका समझौते के विरोध को देखते हुए लगता है कि वयोवृद्ध श्रीलंकाई नेता की राजनैतिक जीवन रक्षा का जिम्मा भी भारत के कंधों पर आ गया है. समझौते पर छाने वाले संशय के बादलों ने श्रीलंका की समझौता विरोधी शक्तियों को नई ताकत दी है. इससे राष्ट्रपति के सामने राजनैतिक अलगाव का खतरा पैदा हो गया है. इस बारे में श्रीलंका के वामपंथी नेता डॉ. कोलविन डि सिल्वा की यह टिप्पणी सटीक जान पड़ती है कि "जयवर्द्धने जितने अलग-थलग अब पड़ चुके हैं वैसा उनकी सत्ता के 10 साल के दौरान कभी नहीं हुआ."

जयवर्द्धने के इस संकट का एक बड़ा प्रमाण 18 जनवरी को देखने को मिला जब उनके बहुचर्चित वित्तमंत्री रोनी डि मेल ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया. डि मेल को जयवर्द्धने का विश्वासपात्र होने के अलावा समझौता समर्थक भी माना जाता रहा है. लेकिन उन्होंने संसद में यह घोषणा करके राष्ट्रपति को खासा सदमा पहुंचाया कि "इससे पहले कि जनता कहे 'भगवान के लिए अब गद्दी छोड़ दो', हमें चुनाव करा लेने चाहिए." इस बारे में विपक्ष के नेता अनुरा भंडारनायके कहते हैं, "रोनी श्रीलंकाई राजनीति की नब्ज पहचानने में माहिर हैं. वे अच्छी तरह जानते हैं हवा का रुख किधर है."

अपने इस्तीफे के बाद डि मेल ने कहा, "सितंबर के बाद समझौते की असफलता ने उन लोगों को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा जो इसकी वकालत कर रहे थे." असलियत यह है कि पार्टी पर जयवर्द्धने के नियंत्रण के बावजूद उनकी सरकार के मंत्री आलोचना के मामले में काफी मुखर होते चले जा रहे हैं. 31 दिसंबर को प्रधानमंत्री आर. प्रेमदास ने एक सार्वजनिक सभा में कहा, "यदि हमारे बच्चे आपस में लड़ते हैं तो क्या यह जरूरी है कि उन्हें डांटने के लिए हम पड़ोसी को बुला लाएं?" और संसद में आंतरिक सुरक्षामंत्री ललित अतुलतमुदाली ने घोषणा कर डाली कि "जनता चाहती है कि भारतीय शांति सेना यहां से वापस जाए."

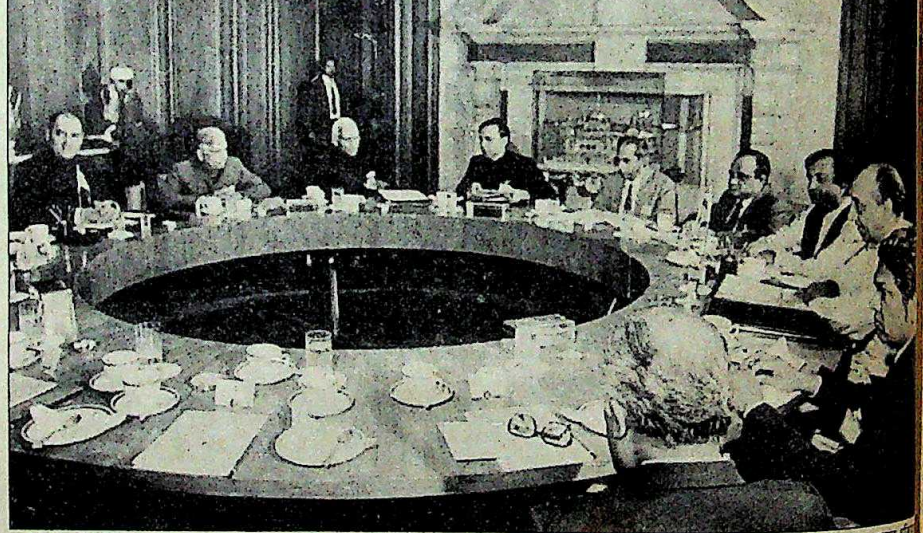

प्रभात पटनायक

जयवर्द्धने की दिल्ली यात्रा के दो मकसद थे— शांति सेना की वापसी के बारे में बातचीत करके सिंहलियों का खौफ दूर करना और दोनों देशों में समान दर्जे के आधार पर संधि की कोशिश करना

उधर शांति सेना के श्रीलंका में लंबे अरसे तक टिके रहने से वहां एक गंभीर मनोवैज्ञानिक संकट खड़ा हो गया है. कोलंबो में होने वाली कॉकटेल और कूटनीतिक पार्टियों में ऐसी अफवाहें जोरों पर हैं कि शांति सेना वहां पांच साल बने रहना चाहती है. इन अफवाहों को उन रिपोर्टों से बहुत बल मिला है जिनके अनुसार शांति सेना जाफना इलाके में पांच साल के अनुबंध पर मकान किराए पर ले रही है.

विडंबना यह भी है कि शांति सेना की मौजूदगी ने श्रीलंका में ऐसी एकता पैदा कर दी है जो राजनैतिक, जातीय और सामाजिक तथा आर्थिक सीमाओं से ऊपर है. प्रधानमंत्री प्रेमदास कहते हैं, "जाफना से लेकर सगरिया दुआ तक हर कोई चाहता है कि शांति सेना वापस चली जाए."

मगर इस परिवर्तन के बावजूद इस बात का खतरा नहीं दिखाई देता कि जयवर्द्धने सरकार बहुत जल्द गिर जाएगी. हालांकि जिस तेजी से जयवर्द्धने जनता से अलग-थलग पड़ते जा रहे हैं वह काफी चिंताजनक है. एक श्रीलंकाई नागरिक रोलैंड गुणतिलके का कहना था, "हमें जयवर्द्धने ने धोखा दिया है. हम स्वयं को दमित और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं." समझौते ने लोगों के मन में बैठी चुनाव की इच्छा फिर से जगा दी है. लोगों के इस मूड को देखते हुए कई मंत्रियों ने भी मौके के मुताबिक रंग बदल लिया है. चुनावों के टाले

जाने के कारण जनता में व्याप्त नाराजगी, भ्रष्टाचार और अब भारत-श्रीलंका समझौते ने श्रीलंका की राजनीति में नया ध्रुवीकरण हो गया है. जयवर्द्धने के खिलाफ जनमत इतना तेज हो चुका है कि एक वरिष्ठ मंत्री की टिप्पणी थी, "यदि अभी चुनावी फैसले लिए जाते हैं तो यूएनपी का हारना तय है."

ऐसी हालत में जयवर्द्धने के पास बचने का एकमात्र रास्ता यही है कि समझौता कामयाबी से लागू हो जाए. राजीव गांधी की तरह अब जयवर्द्धने का भविष्य भी समझौते पर टिका है. पिछले सप्ताह अपनी छह दिन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दिल्ली यात्रा के दौरान जयवर्द्धने का असली लक्ष्य श्रीलंका की जनता को दो मामलों में आश्वस्त करना था. एक तो यह कि शांति सेना एक निश्चित समय के बाद वापस चली जाएगी. उनका दूसरा लक्ष्य भारत के साथ एक समझौता करना है जिससे श्रीलंका की जनता को विश्वास हो सके कि समझौते में दोनों देशों का दर्जा बराबर का है.

पर यदि दोनों देशों के बीच कोई संधि भी होती है तो भी इस तथ्य को अनदेखा नहीं किया जा सकता कि पहले वाला समझौता अब संकट में फंस चुका है. समझौते के अनुसार शांति प्रयासों के तहत दिसंबर 1987 तक क्षेत्रीय परिषद के चुनाव पूरे हो जाने चाहिए थे. पर सचाई यह है कि शांति सेना अभी तक न केवल तमिल चीतों से हथियार रखवा पाने में असमर्थ रही है बल्कि हालत बहाल करने में अभी बहुत समय लगेगा."

हालांकि इस इलाके को तमिल अपना परंपरागत इलाका मानते हैं लेकिन श्रीलंका की सरकारों ने जिस तरह यहां नियोजित तरीके से सिंहली लोगों को बसाया उसे देखते हुए यही लगता है कि प्रस्तावित जनमत संग्रह में इस क्षेत्र को उत्तरी प्रांत में मिलाए जाने का विचार मूर्त्त रूप नहीं ले पाएगा. जनमत के बारे में तमिल आशंकाओं के निवारण के लिए समझौते की पूर्व संध्या पर भारतीय अधिकारियों ने उस अनुच्छेद का जिक्र किया था जिसमें व्यवस्था है कि राष्ट्रपति की इच्छा से प्रस्तावित जनमत स्थगित किया जा सकता है. इस बारे में तमिल नेताओं को परदे के पीछे यह आश्वासन दिया गया था कि जरूरत पड़ने पर भारत जयवर्द्धने को जनमत संग्रह अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करवाने के लिए मना लेगा.

पर अपनी राजनैतिक चतुराई और होशियारी के लिए मशहूर जयवर्द्धने कितनी देर तक भारत की कठपुतली बने रहेंगे, कहना कठिन है. यह संभावना भी है कि वे राजनीति से हटने से पहले इस इलाके में जनमत संग्रह करा डालेंगे.

जहां तक दीर्घकालीन शांति की बात है, जनमत संग्रह के बाद भी इसकी आशा धूमिल है. यदि फैसला एकीकरण के विरुद्ध जाता है तो तमिल चीते 'खोए हुए क्षेत्र' को फिर से हासिल करने के लिए हथियारबंद आंदोलन जारी रखेंगे. इसी तरह एकीकरण के पक्ष में फैसला होने से स्थानीय मुस्लिम और सिंहली आंदोलन के रास्ते पर उतर आएंगे क्योंकि वे जाफना के तमिलों के अधीन रहना नहीं चाहेंगे. इस सिलसिले में त्रिंकोमाली इलाके में सिंहलियों की मोर्चेबंदी और पूर्व में 30 प्रतिशत जनसंख्या वाले मुसलमानों द्वारा मुस्लिम कांग्रेस की स्थापना एक महत्वपूर्ण संकेत है.

इन दोनों प्रांतों में अधिकारियों की हत्या के कारण नागरिक प्रशासन मध्य जनवरी से ही ठप पड़ा हुआ है. 22 जनवरी को मन्नार में तैनात सरकारी अधिकारी एम.एम. मकबूल की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जब वे रामेश्वरम से आए शरणार्थियों के पुनर्वास की व्यवस्था करने के लिए तलाईमन्नार जा रहे थे.

असरदार वित्तमंत्री और समझौते के प्रबल समर्थक रोनी डि मेल के इस्तीफे से साफ मालूम पड़ता है कि जयवर्द्धने अपने मंत्रिमंडल और लोगों से किस कदर अलग-थलग पड़ते जा रहे हैं

इसी दौरान संसद में प्रांतीय परिषदों के चुनाव संबंधी विधेयक को पारित करवाकर जयवर्द्धने ने समझौते में लिखित अपनी एक जिम्मेदारी पूरी कर दी है. नई दिल्ली में साउथ ब्लॉक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्वीकार किया कि "अपनी खोपड़ी उड़वाने का खतरा उठाकर भी राष्ट्रपति जयवर्द्धने ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है. कमी तो भारत की ओर से ही है जो अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रहा है."

इस सबका एक नतीजा कोलंबो सरकार और तमिल चीतों के बीच सीधी गुपचुप वार्ता के रूप में सामने आ रहा है. मद्रास में 12 जनवरी को तमिल चीतों और जेमिनी दिशनायके के बीच बैठक कराने का प्रयास करने वाले ऑल सीलोन तमिल कांग्रेस के नेता जी.जी. पोन्नांबलम का कहना था, "भारतीय रास्ते तो बंद हो चुके हैं इसलिए नए रास्ते खोलना जरूरी हो गया था." भारतीय अधिकारियों ने इस बात की ताईद की कि कोलंबो सरकार तमिल चीतों के साथ एक ओर तो जेमिनी के माध्यम से और दूसरी ओर अतुलतमुदाली के जरिये बातचीत करने की कोशिश कर रही है. पोन्नांबलम कहते हैं, "5 जनवरी को जेमिनी, तमिल चीतों के एक नेता और मैं कोलंबो में महावेली में मिले थे. वहां एक हफ्ते बाद मद्रास में मिलना तय हुआ. इस बैठक के लिए जेमिनी ने राष्ट्रपति की सहमति ले ली थी लेकिन भारतीय उच्चायोग ने इसमें पलीता लगा दिया." स्पष्ट है कि

तमिल छापामार पूर्वी क्षेत्र में, खास तौर से बट्टीकलोआ में फिर से संगठित हो चुके हैं. एक कम्युनिस्ट सांसद देवगुणशेखर कहते हैं, "समस्या का मुख्य केंद्र अब जाफना नहीं बल्कि पूर्वी प्रांत है."

उत्तर में तमिल बहुमत के मुकाबले पूर्वी प्रांत की हालत बहुत पेचीदा है क्योंकि वहां का इलाका और भूगोल अलग होने के साथ-साथ वहां की जनसंख्या में तमिलों, मुस्लिमों और सिंहलियों का अच्छा-खासा मिश्रण है. कानूनमंत्री डॉ. निशंक विजयरत्न स्वीकार करते हैं कि "पूर्व में शांति और सामान्य

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(बाएं से) अतुलतमुदाली, प्रेमदास और दिशनायके: मुख्य दावेदार

भारत मानता है कि इस सीधी बातचीत से उसके हितों को नुकसान पहुंचेगा. सीधी बातचीत में अपनी भूमिका के बारे में अतुलत-मुदाली बेबाक हैं. उनका कहना था, "भला अपने ही देश के नागरिकों के साथ मैं बातचीत क्यों नहीं कर सकता."

पता चला है कि सरकार तमिल चीतों को जाफना प्रायद्वीप का नियंत्रण सौंपने को तैयार है. ऐसी हालत में श्रीलंकाई सेना पूर्व में अपनी 28 जुलाई वाली हालत में आ जाएगी. सरकार का एक तबका यह भी महसूस करता है कि इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाते हुए बिना एकीकरण किए अधिक स्थानीय अधिकार दिए जाएं. पूर्व में एक स्थानीय परिषद की व्यवस्था होगी जो स्थानीय तमिलों, मुस्लिमों और सिंहलियों की तीन अलग-अलग प्रादेशिक सभाओं को अधिक अधिकार देगी. रणनीति के तहत भले ही तमिल उग्रवादी इसे स्वीकार कर लें लेकिन अंततः वे पूर्वी इलाके में अपना हथियारबंद संघर्ष जारी रखेंगे.

यदि समझौता कारगर नहीं हो पाता और कोई नतीजा नहीं निकलता तो सीधी बातचीत को यकीनन गति मिलेगी. भारत के सामने सबसे पहला काम यह है कि श्रीलंका में सामान्य स्थिति बहाल हो जाए ताकि प्रांतीय चुनाव कराए जा सकें.

पूर्वी प्रांत में तमिल चीतों पर काबू पाने के लिए भारत अब पूरा दम लगा देने की रणनीति अपनाने जा रहा है. इस समय वहां 37,000 भारतीय सैनिक हैं. इनकी संख्या 60,000 तक बढ़ाने की योजना है ताकि अप्रैल तक उत्तरी और पूर्वी प्रांतों में तमिल चीतों की विरोध शक्ति को नाकारा किया जा सके. सोचा जा रहा है कि प्रस्तावित प्रांतीय चुनाव मई में कराए जाएं और ये चुनाव शांति सेना की निगरानी में हों. इसके बाद जून में शांति सेना की क्रमबद्ध वापसी का कार्यक्रम शुरू हो ताकि अंत में केवल नाममात्र भारतीय सैनिक वहां रह जाएं. जवयर्द्धने चाहते हैं कि अगस्त में संसदीय चुनाव कराए जाने से पहले ही शांति सेना की वापसी पूरी हो जाए क्योंकि ऐसा होने पर ही उनकी पार्टी मतदाताओं का सामना कर सकती है. उनके दल के सांसद स्वीरासिंहे मल्लीमाराची भी कहते हैं, "शांति सेना की मौजूदगी यूएनपी के लिए बहुत तकलीफदेह है."

योजना के अनुसार संसदीय चुनाव इस साल के अंत तक हो जाने चाहिए. एसएलएफपी ने सिरीमाओ भंडारनायके को राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है. यूएनपी में जयवर्द्धने के उत्तराधिकार के लिए होने वाली खींचतान

भवान सिंह

भंडारनायके: नई चुनौती

अब बाहर भी दिखाई देने लगी है. हालांकि प्रेमदास को पार्टी में दूसरे नंबर का नेता माना जाता है इसलिए जयवर्द्धने द्वारा उन्हें मनोनीत करने की संभावनाएं अधिक हैं. मगर इसके बावजूद किसी पहेली की तरह अबूझ माने जाने वाले जयवर्द्धने पार्टी पर पूरा नियंत्रण बनाए हुए हैं और राष्ट्रपति पद के तीनों दावेदारों— प्रेमदास, अतुलत-मुदाली और दिशनायके को अधर में ही लटकाए हुए हैं. ऐसी अफवाहें भी हैं कि वे शायद अपने पुत्र रवि जयवर्द्धने या भाई हेक्टर जयवर्द्धने के हाथों उत्तराधिकार सौंपने का फैसला करें.

इस संदर्भ में एक बड़ा सवाल यह उठता है कि सत्ता परिवर्तन के बाद समझौते का क्या होगा. खास तौर से एसएलएफपी और जयवर्द्धने के उत्तराधिकारियों के रवैये को देखते हुए यह सवाल उठना वाजिब ही है. इस बारे में एक भारतीय अधिकारी का कहना था कि "यदि एसएलएफपी सत्ता में आती है तो हम उसके साथ सीधी बात करेंगे. हालांकि समझौते पर हस्ताक्षर करने के कारण जयवर्द्धने भारत के सहज सहयोगी हैं लेकिन पिछले चार साल की घटनाओं के बावजूद यह तथ्य नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि एसएलएफपी परंपरा से ही भारत के करीब रही है." विरोधी दलों की परंपरागत शैली में अनुरा ने तो सार्वजनिक घोषणा कर डाली कि "यदि हम सत्ता में आते हैं तो चौबीस घंटे के भीतर ही भारतीय शांति सेना को वापस भेज दिया जाएगा." लेकिन बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि शांति सेना को पूरी तरह वापस भेजना तो संभव नहीं होगा पर उसकी संख्या अलबत्ता जरूर कम करनी होगी.

ऐसी सार्वजनिक लफ्फाजी के बावजूद भारत का विरोध करने वाले सिंहली राजनेता भी मानते हैं कि "श्रीलंका की विदेश नीति को भारतीय मैत्री से अलग करके नहीं देखा जा सकता." अनमने होकर ही सही पर लोग स्वीकार करते हैं कि भारत इस उपमहाद्वीप में एक क्षेत्रीय महाशक्ति बन गया है और नाराज होने की हालत में वह उत्तर और पूर्व में तमिल छापामारों के माध्यम से आसानी से संकट खड़ा कर सकता है.

भारत विरोधी श्रीलंका सरकार यकीनन उत्तर में तमिल विद्रोहियों और दक्षिण में जेवीपी आतंकवादियों के बीच बुरी तरह फंसकर रह जाएगी. इस तरह से परेशान कोई भी सरकार उथल-पुथल में टिकी नहीं रह सकती.

जैसा कि एक भारतीय अधिकारी का कहना है, "यदि श्रीलंका सरकार इस समझौते का आदर नहीं करती और समय से पहले ही शांति सेना को वापस भेजने की जिद करती है तो इसका नतीजा श्रीलंका का बंटवारा ही हो सकता है. यह समझौता ही श्रीलंका की अखंडता की रक्षा कर सकता है." और इसी की आशंका के कारण समझौते के कामयाब होने की उम्मीद की जा सकती है.

—अनीता प्रताप कोलंबो से

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रयोग के लिए जानवरों की सप्लाई

मानो यह शेक्सपीयर के नाटक 'मैकबेथ' की तीन डायनों के भोजन की सूची हो—स्विस अल्विनो माइस, होल्ट्जमैन रैट्स, गोल्डन हेमस्टर्स, गिनी पिग, व्हाइट रेबिट्स और बॉनिट मंकीज. मगर इन चीजों का वास्ता न तो किसी जादू से है और न शेक्सपीयर के मैकबेथ से.

दरअसल ये सब हैदराबाद के राष्ट्रीय पोषण संस्थान (एनआइएन) में चिकित्सा अनुसंधान और तकनीकी प्रयोगों के लिए रखे गए जानवर हैं. इस प्रयोगशाला का उद्घाटन पिछले पखवाड़े ही किया गया. चिकित्सा अनुसंधान में प्रयोग 'किए जाने वाले जानवर पोषण गड़बड़ियों से लेकर कैंसर तक की बीमारियों से निबटने में काफी मददगार साबित होते हैं.

भारत में राष्ट्रीय प्रयोगशाला पशु सूचना सेवा केंद्र, यूनेस्को की मदद से 1956 में बंबई के कैंसर शोध संस्थान में खोला गया था. 1976 में इसे एनआइएन की इमारत में पहुंचा दिया गया पर तब से यह प्रयोगशाला पशु सूचना सेवा केंद्र ऊंचे दर्जे के प्रायोगिक जानवरों की मांग पूरी नहीं कर पाया है.

आज यह केंद्र आठ रुपए में स्विस माउस, 12 रुपए में चूहा, 15 रुपए में हेमस्टर, 30 रुपए में गिनी पिग और 80 रुपए में खरगोश बेचता है. इन दामों में जानवरों की उम्र, लिंग या वजन का कोई ख्याल नहीं रखा जाता. गर्भवती मादा को दुगने दाम पर बेचा जाता है, बशर्ते उसका आर्डर पहले बुक किया गया हो. जैव रसायनज्ञ और केंद्र के प्रमुख डॉ. मेहताब सिंह बामजी (53) कहते हैं, "हमारे संस्थान के प्रायोगिक जानवर कुछ महंगे होंगे क्योंकि वे ज्यादा साफ और खासं किस्म के दड़बों में पाले-पोसे गए होंगे. हम इनके रख-रखाव पर अधिक खर्च करेंगे." केंद्र के विकास के लिए बायो-टेक्नोलॉजिकल विभाग चार साल में 2.20 करोड़ रुपए खर्च करेगा. कई शोध संस्थानों ने वैज्ञानिकों की मांग पूरी करने के लिए पशुशालाएं बना रखी हैं. लेकिन हैदराबाद केंद्र चूहे-चुहियों की सप्लाई राष्ट्रीय स्तर पर करेगा, जबकि लखनऊ का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान वैज्ञानिक शोध का स्तर सुधारने के लिए बंदरों की मांग पूरी करेगा.

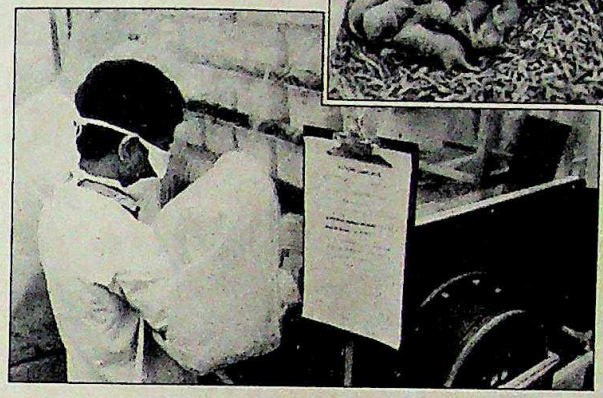

स्विस माइस (दाएं) और नई प्रयोगशाला : रोगों के इलाज में सहायक

दिमाग ही बदल देंगे

● सिर के अंदर की खोज-खबर लेने वाले न्यूरो-सर्जनों ने बंदरों और चूहों में दिमाग की कोशिकाएं प्रतिरोपित करने में भी कामयाबी हासिल की है. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के न्यूरो-सर्जनों की इस कामयाबी ने पार्किसन रोग, एल्झेमायर रोग, फालिज और दिमाग में हुए दूसरी तरह के नुकसानों के इलाज की उम्मीद बंधाई है.

आयुर्विज्ञान संस्थान के पूर्व मुख्य न्यूरो-सर्जन प्रकाश टंडन कहते हैं, "चूहों और बंदरों पर किए प्रयोगों के नतीजें उत्साहवर्धक हैं." आम तौर पर दिमाग की नष्ट हो चुकी कोशिकाएं फिर नहीं बन पातीं. और इस नुकसान को रोकने के लिए कोशिकाओं का प्रतिरोपण ही एकमात्र तरीका है. प्रतिरोपण के लिए बेकार कर दिए गए किसी भी गर्भ के ऊतक लिए जा सकते हैं. स्वीडन, मेक्सिको, चीन, क्यूबा और अमेरिका के वैज्ञानिक मानव मस्तिष्क में कोशिकाएं प्रतिरोपित करने की होड़ में जुटे हुए हैं. कुछ वैज्ञानिकों ने तो यह भी कहा है कि आदमी के दिमाग की कोशिकाएं दूसरे प्राणियों के दिमाग में लगाई जा सकती हैं. पर आदमी के दिमाग के ऊतकों को बेकार कर दिए गए गर्भ के ऊतकों से बदलने के रास्ते में कई तरह के नैतिक सवाल आ खड़े हुए हैं.

बनेगी परमाणु लॉबी

● वैज्ञानिक भी बहुत अजीबोगरीब होते हैं. कई तो भौतिकशास्त्री वगैरह के अपने विशेषण भूलकर इंडियन न्यूक्लियर सोसायटी में शामिल हो गए हैं. जनवरी में बंबई में इस संस्था का उद्घाटन उद्योगपति जे.आर.डी. टाटा ने किया. इसके अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा नियंत्रण बोर्ड के सलाहकार डॉ. एम.वी. रमैया कहते हैं, "यह सोसायटी गैरसरकारी है जो परमाणु विज्ञान, इंजीनियरिंग व तकनीक के विकास के लिए बनी है जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम पर खुले विचार-विमर्श का मंच होगा."

बंबई में वैज्ञानिकों के साथ टाटा (बीच में) : नया मंच

सोसायटी के करीब 700 सदस्य हैं. आम सदस्यता के लिए वार्षिक शुल्क 20 रुपए है और आजीवन सदस्यता शुल्क 200 रुपए. यह आम मुहल्लों में बने नौजवानों के किसी भी क्लब के सदस्यता शुल्क से कम ही है. मुख्यतः परमाणु ऊर्जा विभाग में काम करने वाले ही इसकी ओर आकर्षित हुए हैं. लेकिन योजना यह है कि विद्वानों, परमाणु औषधियों का इस्तेमाल करने वाले और परमाणु ऊर्जा विभाग से जुड़े उद्योगों को इसके साथ भी जोड़ा जाए ताकि एक मजबूत परमाणु लॉबी बन सके जो परमाणु ऊर्जा के बारे में संदेहों को दूर करे.

सुलझेगा दिल दा मामला

● कुछ वॉल्व लंबे समय तक खराब नहीं होते. ऐसे वॉल्व मनुष्य के दिल में हैं. ये चार खानों वाले दिल के दोहरे पंप में खून के बहाव को काबू में रखकर एक ही दिशा में जाने देते हैं और अमूमन इन्हें बदलने की जरूरत नहीं. हृदय रोग वैज्ञानिकों ने आधुनिक स्कैनर्स से नतीजा निकाला है कि देश में हर साल ऐसे 40 हजार वॉल्व बदलने की जरूरत है.

जितने वॉल्व अभी तक लगाए जाते हैं वे इस जरूरत को पूरा नहीं कर पाते. हर साल करीब 4,000 आयातित वॉल्व भारतीय दिलों में लगाए जाते हैं. तिरुअनंतपुरम के श्री चित्र तिरयुनल आयुर्विज्ञान व तकनीक संस्थान के जैवचिकित्सक इंजीनियरों ने अब 'चित्र वॉल्व' बनाया है जो एक साल के अंदर-अंदर लोगों के दिलों में लगाया भी जाने लगेगा.

शरीर रचना के लिहाज से देखें तो आदमी का दिल भेड़ के दिल की तरह ही होता है. संस्थान के शोधकर्ता पिछले 18 महीनों से भेड़ के दिल में 'चित्र वॉल्व' लगाकर तजुर्बे कर रहे हैं. संस्थान ने पहले कुछ वॉल्व टिटैनियम से बनाए थे पर अब नए वॉल्व कोबाल्ट और क्रोमियम के मिश्रण से बनाए जा रहे हैं. संस्थान के निदेशक डॉ. एम.एस. वेलीआथन (54) के अनुसार, "आयातित वॉल्व की कीमत 14,000 रुपए के करीब बैठती है जबकि हम वही वॉल्व 7,000 रुपए में बना लेंगे."

सेबेस्टियन डीसूजा

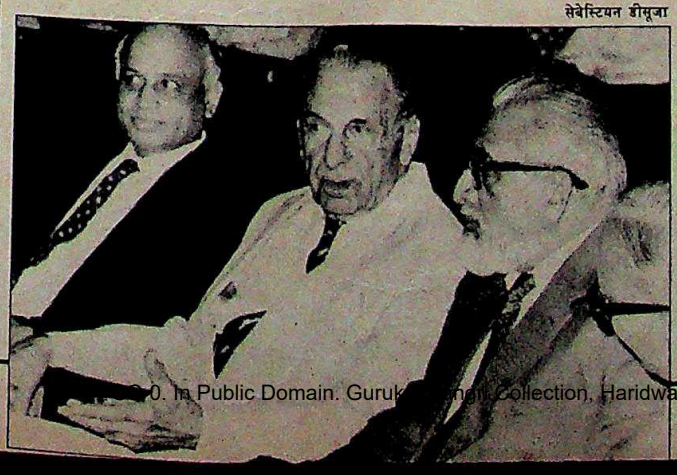

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सिगरेट ही नहीं, चाय भी

सिगरेट के मुख्य कारोबार से थोड़ा अलग हटकर गॉडफ्रे फिलिप्स कंपनी अब देश भर में चाय की बिक्री के केंद्र खोलने जा रही है. ऐसा पहला केंद्र राजधानी में 'टी सिटी' नाम से खुल चुका है. कंपनी को उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में वह देश के चार बड़े शहरों में ऐसे कुछ और केंद्र खोल लेगी. फिर देशव्यापी काम शुरू किया जाएगा.

मोदी समूह की यह कंपनी चाय बागानों और नीलामी केंद्रों से सीधे चाय खरीदेगी और इस प्रकार बिचौलियों को हटाकर लागत खर्च भी कम करेगी. खुली चाय वितरण इकाइयां ही बेचेंगी. चाय खरीदने वालों को इससे भी फायदा होगा.

इस बीच यह चर्चा जोरों पर है कि कृष्ण कुमार मोदी बिजली के समान बनाने वाली जेनरल इलेक्ट्रिकल्स कंपनी और कई अन्य कंपनियों को खरीदने वाले हैं. लेकिन मोदी इसका खंडन करते हैं. जेनरल इलेक्ट्रिकल्स के लोग भी कहते हैं कि कंपनी बिकने वाली नहीं है.

विचित्र परंतु सच

यह बात कुछ अजीब पर सच्ची है. बीएसटी लिमिटेड (पूर्व नाम भारत स्टील ट्यूब) ने अपना वार्षिक शुल्क बंबई से बाहर के चेक से दिया. सिर्फ इसी कारण पिछले 10 दिनों से देश के सबसे बड़े शेयर बाजार में उसका नाम कोट नहीं होता था. बंबई शेयर बाजार का नियम है कि शुल्क स्थानीय चेक या ड्रॉफ्ट से दिया जाए. इसलिए जब इस कंपनी ने किसी बाहरी शहर के खाते वाला चेक जमा कराया तो शेयर बाजार के अधिकारियों ने 11 दिसंबर से बीएसटी का नाम अपनी सूची से उड़ा दिया. नियमानुसार भुगतान करने के बाद ही यह फिर सूची में आ पाया.

जे.के. के इरादे

जे. के. सिंथेटिक्स बड़ी तेजी से दूसरे क्षेत्रों में पैर पसारती जा रही है. हाल में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात का काम शुरू करने के बाद कंपनी अब फोटोग्राफिक फिल्म, एक्स-रे फिल्म और पेपर बनाने जा रही है. उत्तर प्रदेश के प्रदेशीय औद्योगिक निगम के साथ मिलकर यह एक्स-रे व ग्राफिक फिल्म और पेपर बनाने का 400 करोड़ का प्लांट लगाने जा रही है.

वैसे सिंहानिया समूह की यह कंपनी अभी भी फोटोकॉपी उपकरण बनाने की 10 करोड़ रुपए की योजना को सरकारी मंजूरी मिलने की प्रतीक्षा कर रही है. उसे पहले ही अधिकार पत्र मिल चुका है. लेकिन लगता है कि इटली के सहयोग से छोटा विमान बनाने की उसकी महत्वाकांक्षी योजना खटाई में पड़ गई है क्योंकि सरकार अन्य बातों के अलावा छोटे विमान बनाने की तकनीकी जानकारी लेने के सभी पहलुओं पर पुनर्विचार कर रही है.

नए रूप में बिनाका

कभी टूथपेस्ट के साथ जुड़ा विख्यात नाम 'बिनाका' फिर बाजार में धमाका कर सकता है. लेकिन इस बार इसका अवतार ऑफ्टरशेव लोशन, पाउडर, माउथवाश जैसी चीजों के नाम के रूप में होगा. वैसे इस नाम को फिर से बाजार में लाने की सोचने वाली कलकत्ता की कंपनी रेकिट ऐंड कॉलमैन अभी तय नहीं कर पाई है कि वे किस चीज को इस नाम से उतारें. उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में इस बारे में फैसला हो जाएगा. पिछले साल जब सीबा गायगी कंपनी की उपभोक्ता सामान बनाने वाली शाखा को रेकिट कंपनी ने विदेश में ही खरीद लिया तो सीबा इंडिया से बिनाका नाम छिन गया था.

भरमाते हैं आंकड़े

सरकारी आंकड़ों पर थोड़ी सावधानी के साथ भरोसा करना होगा. इंजीनियरिंग उद्योग संबंधी आंकड़ों से ऐसा लगता है कि अचानक यह उद्योग बहुत तेज विकास दर हासिल करने जा रहा है. 1987-88 की पहली तिमाही के ही आंकड़े उपलब्ध हैं और इससे पता चलता है कि विकास दर 20.4 फीसदी है. लेकिन

चार्ट: बी के नर्सी

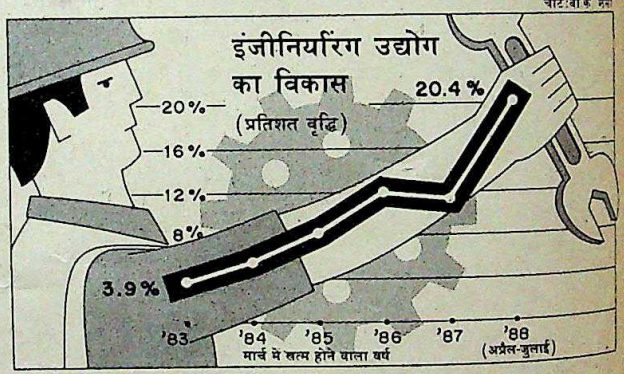

इंजीनियरिंग उद्योग के संगठनों का मानना है कि ये आंकड़े भ्रामक हैं. कंप्यूटर और बिजली उपकरणों में हुई उत्पादन वृद्धि को इसमें शामिल कर देने से ये इतने आकर्षक लगते हैं. अभी तक इन दोनों क्षेत्रों में बहुत कम उत्पादन होता था. कंप्यूटर में 145 और बिजली उपकरणों के उत्पादन में 615 फीसदी की वृद्धि हुई है.

विदेशी ठेकों पर नजर

सरकार परियोजनाओं का निर्यात तेजी से बढ़ाने की रणनीति तय कर रही है. नई योजना उन देशों को केंद्र में रखकर बनाई जाएगी जहां की संरचनात्मक जरूरतें विश्व बैंक, एशिया विकास बैंक और अफ्रीका विकास बैंक जैसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं पूरी करती हैं. पश्चिमी देशों में भारतीय सिले-सिलाए कपड़ों के निर्यात में अब मुश्किलें आने लगी हैं. इसीलिए निर्यात बढ़ाने के क्रम में परियोजनाओं के निर्यात पर ध्यान दिया जा रहा है. अभी तक ऐसी योजनाएं खाड़ी के देशों में ही ली जाती थीं पर वहां भी तेल की कीमत गिरने के बाद की मंदी और प्रतिद्वंद्विता बढ़ते जाने से भारतीय कंपनियों को मुश्किल होने लगी है. नई रणनीति के तहत भारतीय निर्यात कंपनियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर भी ठेके पाने की कोशिश करें.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मीटिंग के दौरान जब मन में उठे चाय की तलब ...

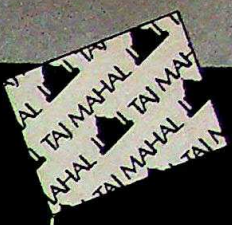

तो डिप लीजिये!

जब आपको झटपट एक कप मनपसन्द चाय की ज़रूरत पड़े, तब ताज महल टी बैग की सुविधा को अपनाइये. न कोई झंझट, न झमेला.

एक कप में एक ताज महल टी बैग रखिये. ताज़ा उबलता पानी डालिये. दो या तीन मिनट तक रखे रहिये. फिर टी बैग निकाल लीजिये. अपने स्वाद के अनुसार दूध और शक्कर मिलाइये. बस, हो गई आपकी चाय तैयार!

कप हो या चायदानी. दोनों में आसानी. (यदि आप चायदानी में चाय बना रहे हैं, तो 4 कप के लिये 3 टी बैग काफी हैं)

ताज महल टी बैग

स्वाद व शान. बनाना आसान!

एक बोंड पैकेट चाय.
हर पैकेट में एक-सी, भरोसेमंद क्वालिटी.

HTA 8620

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रबी

भरपूर पैदावार के आसार

अब तक के अच्छे मौसम के कारण किसानों की उम्मीद बंधी

दिल्ली-मथुरा राजपथ से सटे गेहूं के हरे-भरे खेतों से अपना रास्ता बनाते हुए अजीत सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं था. दूर-दूर तक फैली हरियाली को देखकर लगता था मानो पिछले साल के सूखे की मार की भरपाई हो गई हो. अपने चार एकड़ के फार्म में बड़ी मेहनत से खर-पतवारों को साफ करते हुए अजीत सिंह कहते हैं, "मैंने इस फसल के लिए कर्ज लिया था. मुझे खुशी है कि फसल अच्छी उग आई है. भगवान ने चाहा तो इससे मैं अपना कम-से-कम 50 प्रतिशत घाटा तो मैं पूरा कर ही लूंगा."

अजीत सिंह की ही तरह देश भर के लाखों किसानों की आस रबी की अच्छी फसल पर लगी हुई है. फसल फलने से भरपूर पैदावार की उम्मीद भी जग उठी है. जैसा कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं, "अभी तक मौसम काफी अच्छा है और भारी पैदावार के बारे में हम अभी से सोचने लगे हैं. पर अभी हम कुछ कह नहीं सकते."

हालांकि फसल पकने के दो माह पूर्व पैदावार का ठीक-ठीक अनुमान लगा पाना कठिन है, फिर भी खुशखबरी के कारण मौजूद हैं:—

- पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से बुरी खबरों के बावजूद रबी की मुख्य फसल, गेहूं की 4.8 करोड़ टन की रिकार्ड पैदावार होने की उम्मीद है. इसका श्रेय उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में खड़ी भारी फसल को है.
- काला चना और अरहर की फसलें भी अच्छी हैं और इन फसलों की, 1986 के रिकार्ड 88 लाख टन से कुछ ही कम पैदावार होने की उम्मीद है.
- खरीफ की खराब फसल के बाद तेलहन की फसल कभी इतनी अच्छी नहीं रही. सरसों की 32 लाख टन की रिकार्डतोड़ पैदावार होने की उम्मीद है. यहां तक कि पिछली गर्मियों में भारी नुकसान के बावजूद मूंगफली की फसल भी अच्छी चल रही है.
- दक्षिणी राज्यों में धान की शीतकालीन फसल बहुत अच्छी होने से किसानों के बीच खुशी का माहौल है.

बहरहाल गाढ़े समय में मिला जाड़े का यह उपहार स्वागत योग्य है क्योंकि इधर अनाज आयात करने की चर्चाएं चल रही थीं. पिछले साल की गर्मियों में मौसम की भयंकर मार के मद्देनजर कृषि मंत्रालय ने शुरू में रबी की पैदावार का लक्ष्य 5.5 और 6 करोड़ टन के बीच ही रखा था. (इसमें गेहूं, धान, अनाज और दलहन शामिल हैं). लेकिन जब राज्यों से रबी की अच्छी बुआई और ज्यादा खेतों में फसल उगाने की खबरें आने लगीं तो मंत्रालय ने अपने अनुमान को सुधार लिया और पिछले साल की 6.5 करोड़ टन की पैदावार के मुकाबले इस बार 6.8 करोड़ टन

नक्शा: बी.के. शर्मा

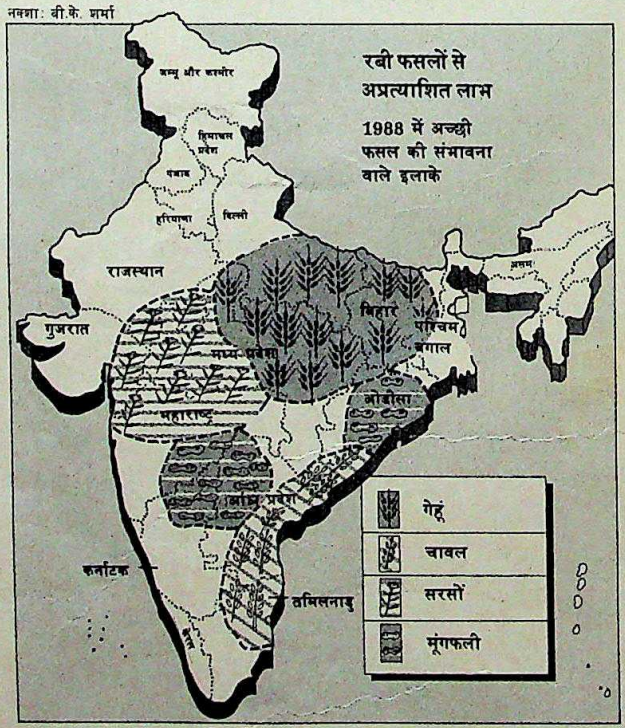

लक्ष्य मुकर्रर किया है.

इससे सिर्फ सरकार ही खुश हो, ऐसी बात नहीं. फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएआइ) के मुताबिक खरीफ की फसल में खाद की खपत 3.3 प्रतिशत गिर गई थी लेकिन रबी की फसल से न सिर्फ इसकी भरपाई ही हुई बल्कि खपत और बढ़ गई है. पर एफएआइ के कार्यकारी निदेशक प्रताप नारायण कृषि मंत्रालय के अधिक[illegible] रियों जैसी बड़ी उम्मीदें नहीं [illegible] रहे. वे कहते हैं, "इस साल रबी [illegible] फसल हमें निराश नहीं करें[illegible] भारी फसल की उम्मीद तो शा[illegible] पूरी न हो पर इस साल पैदा[illegible] पिछले साल के 6.2 करोड़ टन [illegible] तुलना में कम भी नहीं होगी."

बहरहाल कुल मिलाकर [illegible] अच्छी है. देश के मुख्य आ[illegible] खरीफ की फसल खराब हो जाने [illegible] अनाज का भंडार गड़बड़ा गया [illegible] ताजे अनुमानों के अनुसार [illegible] की कुल पैदावार 6.76 करोड़ [illegible] के आसपास है. यह पिछले साल [illegible] मुकाबले 1.4 करोड़ टन कम [illegible] अनाज के भंडार खाली होते जा[illegible] अकाल जैसी स्थिति की रोकथा[illegible] लिए देश में सालाना कम-से-[illegible] 13 करोड़ टन अनाज की पैदा[illegible] बहुत जरूरी हो गई है. इस [illegible] रबी की 6.8 करोड़ टन की भारी पैदा[illegible] अनाज का भंडार 13 करोड़ टन से [illegible] हो जाएगा लेकिन इसके बावजूद देश [illegible] की सीमा से बाहर नहीं हो पाएगा.

रबी की खराब फसल से संकट [illegible] जाएगा, इसका अभास होते ही अमूमन [illegible] रहने वाली केंद्र तथा राज्य सरकारें [illegible] जरूरी सामान मुहैया कराने के लिए [illegible]

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रशांत पंजियार

गेहूं के लहलहाते खेत: उम्मीद की किरण

उठी. चूंकि रबी फसलों में तीन-चौथाई गेहूं की ही पैदावार होती है, इसलिए सरकार ने इसी की बुआई पर ज्यादा ध्यान दिया.

जब बिहार से बुआई के लिए तीन लाख टन गेहूं के बीजों की कमी पड़ने की खबर आई तो केंद्र सरकार ने पड़ोसी राज्यों से तुरंत अनाज लेकर उसे दिया. खेती का मौसम शुरू होने से बहुत पहले राज्यों से खाद की जरूरतों के बारे में जानकारी मंगा ली गई थी ताकि बाद में कमी न पड़े. उधर बैंकों से जरूरतमंद किसानों को कर्ज बांटने को कहा गया. मसलन पंजाब में जब ट्यूबवेल सूख गए तो बैंकों ने नए कुएं खोदने के लिए 250 करोड़ रुपए के कर्ज बांटे (पिछले साल 120 करोड़ रुपए के कर्ज बांटे गए थे). विडंबना ही है कि खरीफ की खराब फसल से रबी फसलों की बुआई के लिए किसानों में उत्साह पैदा किया. सूखे के कारण जिन किसानों ने अपने खेतों को खाली छोड़ दिया था, अक्तूबर में पहली बारिश पड़ते ही वे गेहूं की बुआई में लग गए. देश के गेहं-बहुल उत्तर भारत में हमेशा की तुलना में 15-20 दिन पहले ही बुआई शुरू हो गई. दक्षिण-पश्चिमी मानसून के इस बार न आने से कीड़ों का प्रजनन रुक गया. आम तौर पर ये कीड़े कुल फसल का दसवां भाग नष्ट कर डालते हैं.

बिहार में खरीफ फसल को साफ करने वाली बाढ़ ही रबी की फसल के लिए वरदान साबित हुई. बाढ़ के पानी के कारण जमीन में नमी की सतह ऊंची हो गई थी. इससे किसानों ने बुआई जल्दी शुरू कर दी. गेहूं की खेती आठ लाख हेक्टेयर अधिक की गई. दरअसल गेहूं उपजाने वाले अधिकांश राज्यों में किसानों ने खरीफ का घाटा पूरा करने के लिए गेहूं की अधिक खेती की. उत्तर प्रदेश में गेहूं की खेती में चार लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई. मध्य प्रदेश से भी अच्छी फसल होने की खबरें मिलीं.

लेकिन सब कुछ उम्मीदों के मुताबिक नहीं चल रहा. गेहूं की 80 प्रतिशत खेती सिंचित जमीनों में ही होती है पर गर्मियों में बारिश कम होने से पंजाब में अनेक ट्यूबवेलों का जल स्तर एक मीटर नीचे चला गया और बहुत से सूख गए. हरियाणा में नहरों में पानी का स्तर सामान्य से आधा रह गया था. इन राज्यों में बिजली की कमी भी बनी रही है. इन कारणों से किसानों द्वारा नए ट्यूबवेल लगाने या पंपसेट चलाने के लिए डीजल के प्रयोग से रबी की फसल पर लागत खर्च 15 प्रतिशत बढ़ जाने की उम्मीद है.

पंजाब में स्थिति बेहतर है. राज्य सरकार का कहना है कि पैदावार 95 लाख टन की औसत तक पहुंच जाएगी. हरियाणा और पंजाब की बुरी खबरों के बावजूद उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में भारी फसल होने की उम्मीद से राष्ट्रीय प्रेक्षकों के चेहरों पर खुशी झलकती है.

देश में गेहूं के कुल उत्पादन का 36 प्रतिशत उत्तर प्रदेश से आता है. राज्य के कृषि सचिव रवि मोहन सेठी ने कहा, "अगर एक और बारिश हो जाए तो पिछले साल की 1.65 करोड़ टन पैदावार के मुकाबले इस साल 1.9 करोड़ टन पैदावार हो सकेगी." उधर बिहार सरकार का भी कहना है कि राज्य में फसल अच्छी है.

लेकिन एक विशेषज्ञ की राय में स्थिति अभी "कुल मिलाकर संदेहास्पद है." कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे रबी की फसल बहुत अच्छी भी हो सकती है और बरबाद भी. मसलन अगले पखवाड़े अगर बारिश हो जाती है तो उससे बारिश पर आधारित फसलों को तो फायदा होगा ही, इसका असर पूरी फसल पर भी पड़ेगा. फसल पकने के समय बारिश हुई या ओले पड़े तो अच्छी खड़ी फसल भी बरबाद हो सकती है. हरे-भरे खेत कटाई से पहले अगर सुनहरे हो गए तभी पता चल सकेगा कि पैदावार उम्मीदों पर खरी उतरी है या नहीं.

—राज चेंगप्पा और ब्यूरो रिपोर्ट

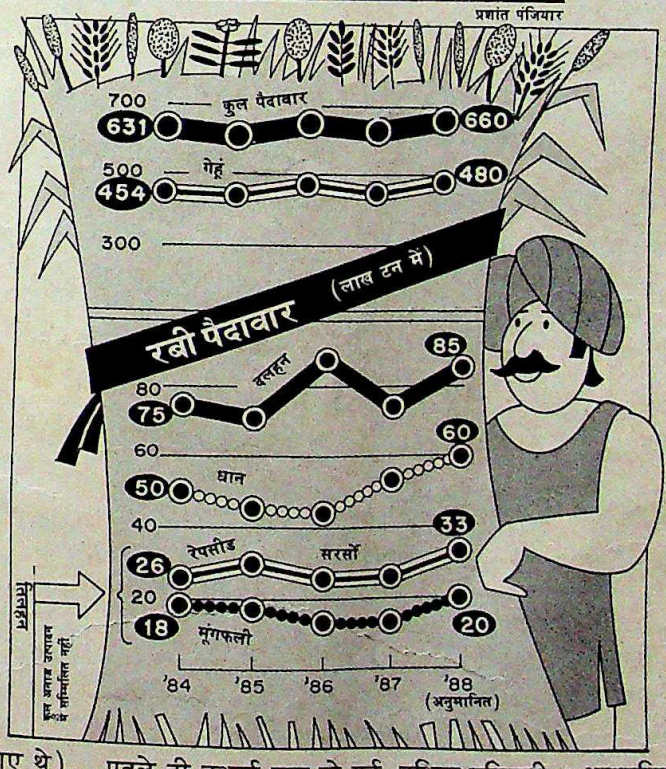

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सार्वजनिक उपक्रम

एक बार फिर कसौटी पर

सरकार इसमें सुधार के कई उपाय सोच रही है

प्रधानमंत्री राजीव गांधी भले ही सार्वजनिक क्षेत्र से जितनी नाक-भौं सिकोड़ें सार्वजनिक क्षेत्र के 214 प्रतिष्ठानों में भारी बदलाव हो सकते हैं. अभी जिन बातों पर अमल हो रहा है उनमें आंशिक निजीकरण (25 फीसदी शेयर कर्मचारियों और लोगों को दिए जा सकते हैं), लगातार घाटा दे रहे प्रतिष्ठानों को बंद करना और बेकार होने वाले मजदूरों के लिए एक कोष बनाना शामिल है.

इतना ही नहीं, कंपनियों को कई मामलों में सरकारी नियंत्रण से बाहर होने दिया जाएगा. अपने सामान की कीमत तय करने, अपने कर्मचारियों से वेतन सुविधाओं के लिए सौदा करने और वेतन के एक-तिहाई हिस्से को उत्पादकता से जोड़ने के अधिकार भी उन्हें मिलेंगे.

आजादी देने के लिए सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की और इकाइयों के, जिनमें घाटे वाली इकाइयां भी शामिल हैं, साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने जा रही है. सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को आपसी सहयोग से संयुक्त उपक्रम शुरू करने की अनुमति भी मिल सकती है. साथ ही तैयार माल की क्वालिटी देखने के लिए सरकार किसी बाहरी समूह को जिम्मा सौंप सकती है.

संभावित बदलावों में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के प्रबंधक मंडलों में सरकारी अधिकारियों की संख्या कम करना और हर कंपनी को एक छोटी सूची सौंपना कि सरकार उनसे क्या-क्या चाहती है, शामिल है. इसी के आधार पर उनके वार्षिक कामकाज का मूल्यांकन किया जाएगा. सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के प्रमुखों की शिकायतों के मद्देनजर महालेखाकार और सार्वजनिक उपक्रम की संसदीय कमेटी के कई ऑडिटों वाली व्यवस्था ढीली होगी.

'बीमार' चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों के इलाज की ये कुछ दवाइयां उस श्वेत पत्र में भी बताई गई हैं जिसे सरकार जल्दी ही संसद में लाने जा रही है. कुछ बातें सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के प्रमुखों की बैठक में भी सामने आईं. अधिकांश प्रस्ताव तो मान जाएंगे पर कुछ राजनैतिक रूप से इतने हंगामाखेज हैं कि शायद ही उन पर अमल हो.

इस सबके बावजूद ये प्रस्ताव शिथिल हो गए सार्वजनिक क्षेत्र को जगाने की नई कोशिश जरूर साबित होंगे. हाल के महीनों में सरकार ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल), भारी इंजीनियरिंग निगम (भेल) और राष्ट्रीय ताप ऊर्जा निगम के साथ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं जिनमें बताया गया है कि बिना अधिकारिक अनुमति लिए वे क्या-क्या कर सकते हैं. इसमें उनके उत्पादन लक्ष्य भी बताए गए हैं. अधिक स्वायत्तता देने के क्रम में सरकार ने इन इंजीनियरिंग उद्यमों के लिए नियंत्रण कंपनियां भी बना हैं. साथ ही इसमें 20 करोड़ रुपए तक के निवेश के लिए स्वतंत्र फैसले करने की अनुमति भी दी गई है. कुछ मामलों में इन प्रतिष्ठानों के प्रमुख लोगों को पांच साल का कार्यकाल दिया गया है. अभी तक सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों को सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख पदों पर लाने के लिए सार्वजनिक उद्यम चयन परिषद का पुनर्गठन करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं.

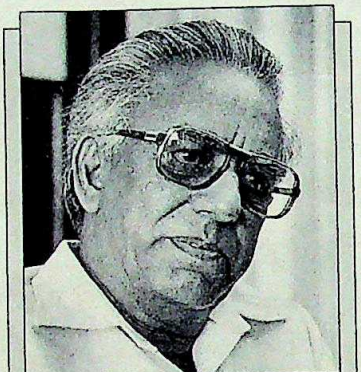

"व्यापार सरकारी तौर-तरीके से नहीं चल सकता. इसे व्यापार के तरीके से ही चलाना होगा. इसका एहसास सबसे पहले खुद सरकार को ही होना चाहिए"

वी. कृष्णमूर्ति
अध्यक्ष, 'सेल'

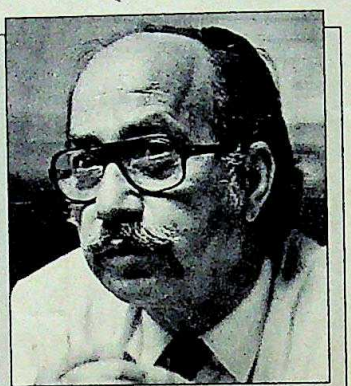

"जिन नौकरशाहों को सार्वजनिक क्षेत्र के लोग अपने कामकाज का ब्यौरा देते हैं उन्हें खुद किसी गलती के लिए जवाबदेह नहीं माना जाता"

एस.पी. वाही
अध्यक्ष, 'ओएनजीसी'

चार्ट: बी.के. शर्मा

सार्वजनिक क्षेत्र का कारोबार

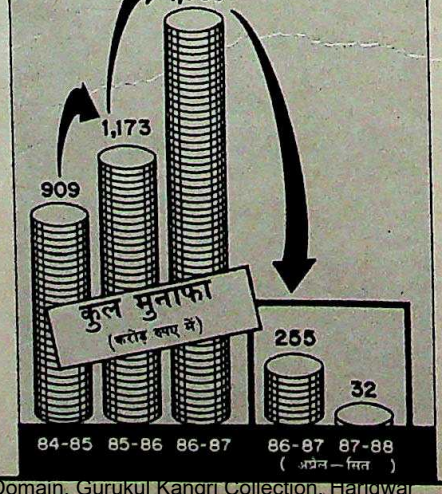

सार्वजनिक क्षेत्र की अधिकांश कंपनियां पूंजी और संसाधन जुटाने के मामले में असफल रहीं. सातवीं योजना के पहले तीन वर्षों में कमी 30 फीसदी रही. लक्ष्य 21 करोड़ रुपए का था. इससे भी बुरी बात हुई है कि 1987-88 की पहली छमाही मुनाफा पिछले वर्ष की इसी अवधि के करोड़ रुपए की तुलना में 32 करोड़ पर आ गया जबकि पूंजी निवेश करोड़ रुपए का हुआ.

लेकिन अभी भी कई लोग आशा हुए हैं. सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के सचिव सुरेश कुमार कहते हैं, "सातवीं के लिए तय आंतरिक संसाधन का में मुझे कोई मुश्किल नहीं दिखती. दो वर्षों में बढ़ना ही है." लेकिन कामकाज से निराश हो चुके लोगों

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ज्यादा मजबूत हैं. वित्त मंत्रालय ने जिन 61 सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का अध्ययन किया उनमें से 10 ने तो 1986-87 की पहली छमाही में नाममात्र के भी आंतरिक संसाधन नहीं जुटाए (चार्ट देखें). इसलिए इनके इलाज के सारे सूत्र बहुत संभालकर जुटाने होंगे और इन उपक्रमों को अधिक व्यावसायिक ढंग से चलाना होगा.

यहां यह सवाल महत्वपूर्ण है कि क्या ये उपाय भी कारगर होंगे? पर यह परीक्षा भी तभी हो सकती है जब सरकार इन उपायों को लागू करे. सार्वजनिक क्षेत्र के कई बड़े अधिकारी निजी बातचीत में इस बारे में संदेह ही जाहिर करते हैं. 'सेल' के अध्यक्ष वी. कृष्णमूर्ति ने चेतावनी दी, "व्यापार सरकारी तरीके से नहीं चल सकता. इसे व्यापार के तरीके से ही चलाना होगा. और इस बात का एहसास सबसे पहले खुद सरकार को होना चाहिए." ओएनजीसी के अध्यक्ष कर्नल एस.पी. वाही ने स्पष्ट रूप से कहा कि सहमति पत्र की शर्तें उचित नहीं हैं क्योंकि जिन नौकरशाहों को सार्वजनिक क्षेत्र के लोग अपने कामकाज का ब्यौरा देते हैं, उन्हें खुद किसी गलती के लिए जवाबदेह नहीं माना गया है. फिर, होल्डिंग कंपनियां वास्तविक स्वायत्तता नहीं देतीं. व्यवहार में सरकार नियुक्ति और पूंजीनिवेश का अधिकार इन इकाइयों के प्रबंधक मंडलों को सौंपने की इच्छुक नहीं रही है. कृष्णमूर्ति इस बात की पुष्टि करते हैं, "होल्डिंग कंपनियां तभी काम कर सकती हैं जब सरकार उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने का मौका दे."

करीब साल भर पहले सरकार ने घाटे में चल रही दो-तीन कंपनियों को बंद करने का फैसला किया. यह फैसला ज्यादा बड़ा सिरदर्द साबित हुआ क्योंकि हर जगह कर्मचारियों के बेरोजगार होने का शोर मचना शुरू हो गया. इसलिए सारे उपाय कर लेने के बाद ही घाटे वाली कंपनियों को बंद करना मुश्किल होगा. दूसरी समस्याएं भी हैं. इन कंपनियों के शेयर कौन उठाएगा. फिर उत्पादकता से वेतन को जोड़ने पर मजदूर संघ हंगामा मचाएंगे ही. 'भेल' के कार्मिक निदेशक माधव राव ने भी यही सवाल उठाया, "किस देश में उत्पादकता से जुड़ा वेतनमान कौन मजदूर संघ मान सकता है?"

उसके बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र को काम करने लायक बनाने की सरकारी चिंता को समझा जा सकता है. दृढ़ इच्छाशक्ति हो तो कठोर फैसले किए जा सकते हैं. सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान एक बार फिर कसौटी पर कसे जाएंगे और तब उनके दिन सुधर सकते हैं.

—सुरजीत बासगुप्त

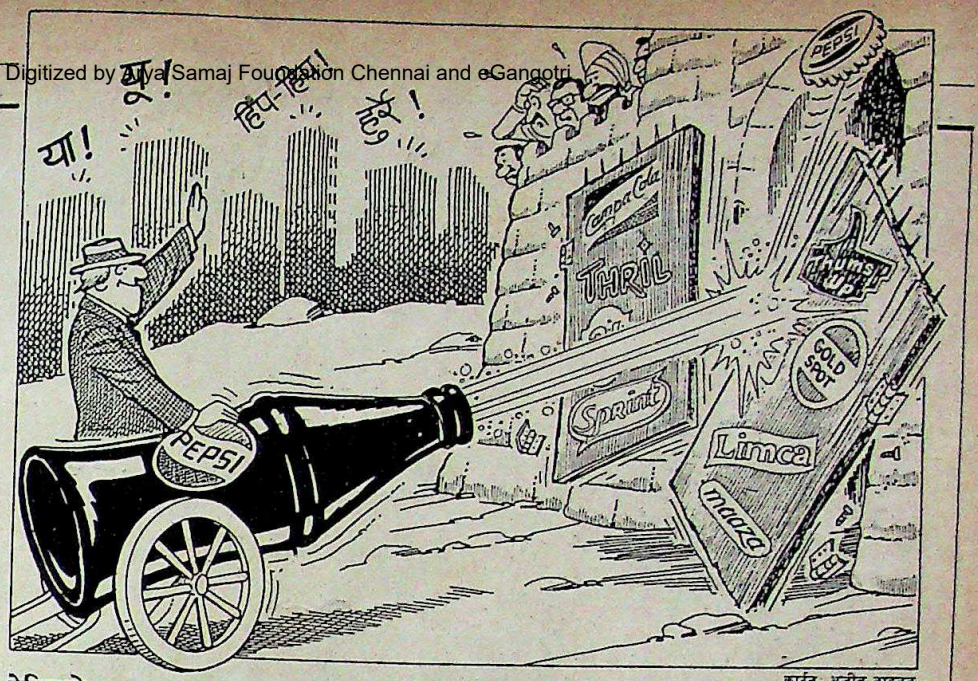

कार्टून: अजीत नाइनन

पेप्सिको

मिली हरी झंडी

शीतल पेय बाजार गरमाएगा

अमेरिकी खाद्य सामग्री निर्माताओं के सिरमौर पेप्सिकौ के लिए भारतीय बाजार के दरवाजे आखिरकार खुलते नजर आ रहे हैं. पेप्सिको ने तीन साल पहले शीतल पेय बनाने और उसके निर्यात की एकमुश्त योजना के साथ यहां दस्तक दी थी. सरकार के योजना मंजूरी बोर्ड ने अंततः पिछले महीने पेप्सिको और उसके स्थानीय साझेदारों—पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन तथा वोल्टाज़—को इस विवादास्पद योजना के लिए हरी झंडी दिखा दी.

वैसे, अभी भी एक रुकावट बची ही है. प्रस्ताव अभी एक विशेष संसदीय समिति के पास पड़ा हुआ है. वित्तमंत्री नारायणदत्त तिवारी द्वारा संसद में किए एक वायदे के मुताबिक प्रस्ताव को इस समिति के हवाले किया गया था. पर यह बड़ी बाधा नहीं.

पेप्सीको को कई शर्तों से बांधा गया है. इसे अपने धंधे की कुल जमा बिक्री का आधा निर्यात करना होगा. साथ ही इसका शीतल पेय का धंधा किसी भी हालत में पूरे धंधे के एक चौथाई से ज्यादा नहीं होना चाहिए. सामान्य नियमों के तहत इस तरह की परियोजना में विदेशी ब्रांड नाम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिए पेप्सीकोला नाम भारत में इस्तेमाल नहीं हो सकेगा. शायद इसीलिए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने और विदेशी सहयोगी लेने के लिए जरूरी आवेदन देते वक्त पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज ने अपने उत्पाद का भारतीय नाम रखने का वादा किया हुआ है.

इन सारी शर्तों के बावजूद परियोजना शुरू करने वालों में संतुष्टि का भाव बहुत मुखर है. एक बात तो तय है कि शीतल पेय का धंधा निश्चित सीमा में ही चलाने की पाबंदी के बावजूद पेप्सी देश के कुल शीतल पेय बाजार के एक चौथाई पर आसानी से कब्जा जमा सकती है. अगर ऐसा हो जाता है तो पेप्सी बहुत जल्दी इस धंधे में दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगी. पहले नंबर पर पारले एक्सपोर्ट है जिसने थम्स अप, लिम्का, गोल्ड स्पॉट और माज़ा के साथ देश के दो तिहाई बाजार पर कब्जा जमा रखा है.

अपनी कुल बिक्री का आधा निर्यात करने की शर्त का मतलब है कि कंपनी को 10 साल में 150 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का निर्यात करना पड़ेगा जबकि पेप्सी ने शुरू में वादा किया था कि वह परियोजना के लिए जरूरी विदेशी मुद्रा का तीन गुना निर्यात करेगी. यानी पांच साल में 50-60 करोड़ रुपए का निर्यात. परियोजना तैयार करने वालों का कहना है कि यह एक कड़ी शर्त है. पर वे इसके विकल्प भी तलाश रहे हैं. इनमें से एक विकल्प है कि पंजाब से फलों का अर्क निर्यात करने के अलावा मसाले भी स्वतंत्र रूप से बाहर भेजे जाएं. एक और विकल्प यह है कि फलों का अर्क निकालने के जम्मू-कश्मीर वाले कारखाने को कंपनी अपने हाथों में ले ले. कुछ समय से यह बंद पड़ा है.

अगर संसदीय समिति इसे हरी झंडी दिखा देती है तो निश्चित ही देश के शीतल पेय बाजार में उथल-पुथल शुरू हो जाएगी. हालांकि इधर कुछ सालों में भारतीय बाज़ारों में विदेशी नामों के बहुत से उत्पाद आए पर किसी को ज्यादा कामयाबी नहीं मिली (एक उदाहरण रॉथमैन सिगरेट है). पेप्सी ने जो दमखम, लचीलापन और उद्यमशीलता दिखाई है उससे लगता है कि यह कंपनी आसानी से हार नहीं मानेगी.

—टी.एन. नाइनन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पोलिएस्टर उद्योग

ग्रहदशा खराब

कई उद्योग बंद होंगे

कुछ दिन पहले पोलिएस्टर मिल लगाना हर उद्योगपति का सपना हुआ करता था. मोटा मुनाफा और पोलिएस्टर कंपनियों की चमत्कारी प्रगति नए उद्योगपतियों की प्रेरणास्रोत थी. आखिरकार रिलायंस उद्योग भी पोलिएस्टर उत्पादन की बदौलत ही इतना आगे बढ़ पाया.

लेकिन अब हालात तेजी से बदलते जा रहे हैं. लाभ की गिरती दरों ने प्रबंधकों को उत्पादन धीमा करने पर मजबूर कर दिया है. पोलिएस्टर कंपनियों की शेयर कीमतें भी तेजी से लुढ़की हैं. पोलिएस्टर उद्योग के मोटे मुनाफे से इस ओर आकर्षित होने वाले उद्योगपति भी अब मुश्किल में फंस गए हैं.

रिलायंस के कार्यकारी निदेशक अनिल अंबानी कहते हैं, "मुझे नहीं लगता कि पोलिएस्टर उद्योग से ज्यादा खस्ताहाल कोई और उद्योग है." ओडीसा सिंथेटिक जैसी कई कंपनियों की तरह रिलायंस समूह भी पिछले 12 महीनों में 60,000 टन क्षमता वाली अपनी फाइबर मिल को तीन महीने तक बंद रखने पर मजबूर हो गया था. इंडिया पोलिफाइबर लिमिटेड (आइपीएल) जैसी कुछ और कंपनियां भी इस बारे में सोच-विचार कर रही हैं. इस कंपनी के हर्ष गोयनका कहते हैं, "हमारे सामने मिल बंद करने के अलावा कोई और चारा नहीं रह गया. जमा स्टॉक बढ़ता जा रहा है और मांग है ही नहीं."

देश में पोलिएस्टर उत्पादन क्षमता का सिर्फ एक तिहाई ही इस्तेमाल हो रहा है फिर भी करीब दो महीने भर की मांग के लायक माल स्टॉक में है. इंडियन आर्गेनिक केमिकल्स के प्रबंध निदेशक श्याम धिया बताते हैं, "जब पोलिएस्टर की मांग कम थी तो दूसरे लोगों की तरह हमने भी अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा ली थी. अब हम कुल क्षमता का केवल 40 प्रतिशत ही उपयोग कर रहे हैं." निकट भविष्य में दो और नए बड़े कारखानों के काम शुरू करने से हालत और बिगड़ेगी. ये हैं: सार्वजनिक क्षेत्र की बोंगाईगांव रिफाइनरीज़ और थापर समूह की पंजाब पोलिफाइबर. इन दोनों मिलों में 60,000 टन रेशे का उत्पादन होगा. इससे देश में रेशे का उत्पादन दो लाख टन हो जाएगा. इसकी मांग 75,000 टन से ज्यादा नहीं है.

पोलिएस्टर फिलामेंट धागा तैयार करने वाली इकाइयों की हालत में इधर थोड़ा सुधार हुआ है. पिछले अठारह महीनों से धागे की कीमतें गिरी हुई थीं. अब इसकी मांग बढ़ जाने के कारण कीमतें कुछ बढ़ी हैं. ओरके के सिल्क मिल्स के एक प्रवक्ता के अनुसार, "मांग जरूर बढ़ी है पर कीमतों में उतनी वृद्धि नहीं हो पाई है, जितनी हम चाहते थे." 'इंडियन आर्ट सिल्क वीविंग इंडस्ट्री' के उपाध्यक्ष जमनादास मूरजानी कहते हैं कि कुछ महीने पहले के 145 रुपए प्रति किलो के मुकाबले अभी धागे की कीमतें 160 रुपए तक पहुंच गई थीं.

धागे की मांग बढ़ने से कई कंपनियों के वित्तीय कामकाज में सुधार हुआ है. ओरके के शेयरों की कीमतें 190 रुपए से 19 रुपए रह गई थीं. 1987-88 की पहली छमाही में उसने पिछले वर्ष के पूर्वार्द्ध के मुकाबले चारगुना कर-पूर्व मुनाफा कमाया है (2.08 करोड़ के मुकाबले 8.10 करोड़). उसके शेयर की कीमतें भी 19 रुपए से बढ़कर 26 रुपए हो गई हैं. रिलायंस ने भी साल के आठ महीनों में 31 करोड़ रुपए का मुनाफा दिखाया है, जबकि 1986 में पूरे वर्ष में इसने कुल 14.17 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था.

जेके सिंथेटिक्स ने भी इस साल की पहली छमाही में 7.50 करोड़ रुपए का मुनाफा दिखाया है. पिछले वर्ष के पूर्वार्द्ध में इसे 3.40 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था. ऐन्का सेंचुरी ने, जो इस कठिन दौर से भी अप्रभावित ही रही थी, अपना अर्द्धवार्षिक लाभ 4.38 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4.76 करोड़ रुपए कर लिया है.

"मुझे तो नहीं लगता कि पोलिएस्टर उद्योग से ज्यादा खस्ताहाल दूसरा कोई और उद्योग है"

अनिल अंबानी
कार्यकारी निदेशक, रिलायंस

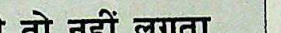

"मांग कम थी और हमने उत्पादन क्षमता बढ़ा ली. हम 40 फीसदी क्षमता का ही उपयोग कर रहे हैं"

श्याम धिया
प्रबंध निदेशक, आइओसी

इस समस्या को कुछ हद तक तो सरकार ने ही बढ़ावा दिया है. पिछले कुछ हफ्तों में सरकार के कपड़ा उत्पादन शुल्क संबंधी नितांत अव्यावहारिक निर्णयों ने उद्योग में खलबली ही मचा दी है. इससे रेशा और धागा दोनों की मांग घट गई है. पिछले पखवाड़े के टैक्स परिवर्तनों (पिछले दो महीनों में तीसरी बार ये परिवर्तन किए गए हैं) और निर्यात प्रोत्साहन योजना से मांग बढ़ने की उम्मीद है.

सभी रेशा निर्माता स्वीकार करते है कि मांग और उत्पादन में इतना बड़ा फासला होने के कारण बिना भारी बदलाव किए वे ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे. उद्योग ने सरकार के सामने दो मांगें पेश की हैं—रेशे पर उत्पादन शुल्क 25 रुपए प्रति किलोग्राम से घटा कर 2.50 रुपए किया जाए, निर्यात को बढ़ावा देने की उदार वित्त सहायता योजना बने. एक रेशा उत्पादक ने कहा कि पिछली बार रेशे का उत्पादन शुल्क 45 रुपए प्रति किलोग्राम से घटाकर कर 25 रुपए किया गया था तो मांग एक ही साल में 53 फीसदी बढ़ गई थी. सरकार मदद करे तो ऐसा फिर हो सकता है. जबकि कुछ उत्पादक मानते हैं कि वित्तीय मुश्किलें ढीली फंसी तथा सूखे और सुरक्षा पर खर्चों से परेशान सरकार और रियायतें नहीं दे सकती.

यह स्थिति है भी पर यदि सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया तो निकट भविष्य में कई पोलिएस्टर फाइबर कंपनियां मुश्किल में पड़ जाएंगी. धागा उत्पादक भले ही इस संकट से उबर जाएं लेकिन पोलिएस्टर उद्योग में पहले जैसी चमक-दमक नहीं लौट पाएगी.

—टी.एन. नायर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ठाकरसी घराना

बंटवारे की ओर

मर्चेंट की संतानों का दावा

महान क्रिकेट खिलाड़ी विजय मर्चेंट की दोनों संतानों के लिए यह खेल क्रिकेट से कहीं अधिक मुश्किल है. उनके चचेरे भाइयों ने जैसे 'गुगली' गेंद फेंक दी है. लेकिन मर्चेंट की 32 वर्षीया बेटी अदिति और 29 वर्षीय बेटे अमर का विकेट अभी उखड़ा नहीं है. वे इस 'गेंद' को सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने अदालत में अर्जी लगा दी है.

विवाद का मुद्दा है—90 करोड़ रुपए के कारोबार वाले ठाकरसी घराने में घोटाले. इस औद्योगिक साम्राज्य में कपड़ा, कपड़ा उद्योग की मशीनें और कार्बनिक एसिड बनाने वाली कंपनियां शामिल हैं. और दांव पर लगी है घराने की कम-से-कम एक बड़ी कंपनी के प्रबंधक मंडल में मर्चेंट के बेटे और बेटी की जगह.

पिछले पखवाड़े यह विवाद तब खुलकर सामने आ गया जब पुलिस ने बीच बंबई में ठाकरसी समूह के मुख्यालय पर छापा मारा. आठ घंटे के छापे में पुलिस ने वहां से ढेर सारे दस्तावेज जब्त किए और उन्हें आठ बोरियों में भरकर ले गई.

यह छापा विजय मर्चेंट की बेटी अदिति संथानम की शिकायत पर मारा गया. उनका आरोप था कि उनके चचेरे भाइयों सुधीर और चंद्रहास ने 9.85 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है. इस समूह की सबसे प्रसिद्ध और 82 करोड़ का कारोबार करने वाली कंपनी हिंदुस्तान स्पिनिंग ऐंड वीविंग मिल्स लिमिटेड में 1986 में मर्चेंट की एक निवेश कंपनी ने यह पैसा जमा कराया था. शिकायत है कि यह पैसा वापस नहीं लौटाया गया. नवंबर में इस पैसे की मांग की गई थी. कंपनी के वकीलों ने कहा कि दोनों पक्षों और 'बुफोटेक्स' के बीच समझौता होने के बाद पैसा लौटा दिया गया है. 'बुफोटेक्स' में मर्चेंट के बेटे-बेटी और मर्चेंट के भतीजों का हिस्सा है. पर अमर का कहना है, "लेकिन हमें बुफोटेक्स से चेक से पैसा निकालने का अधिकार नहीं है."

सचाई चाहे जो हो, ठाकरसी समूह अभी उथलपुथल के दौर से गुजर रहा है. इस समूह में घाटे में चल रही सिरदार कार्बनिक गैस और मुनाफे वाली इक्क हॉबोल्ड और लक्ष्मी के अलावा कई छोटी कंपनियां भी हैं. अधिकांश का नियंत्रण या मिल्कियत इसी परिवार के पास है. इन कंपनियों को परिवार की तीन शाखाओं (वंशवृक्ष देखें) के लोग चलाते हैं. हर शाखा के पास समान शेयर हैं पर उनके निवेश का तरीका बहुत उलझा हुआ है जिसमें कई निवेश कंपनियां भी शामिल हैं.

पिछले अक्तूबर में मर्चेंट की मृत्यु के पहले तक घराने की हरेक कंपनी के प्रबंधक मंडल में परिवार की हर शाखा को प्रतिनिधित्व मिला हुआ था. मर्चेंट सिरदार कार्बनिक, हॉबोल्ड और लक्ष्मी के अध्यक्ष थे. उनके भतीजे सुधीर, जो टेबल टेनिस के राष्ट्रीय चैंपियन रह चुके हैं, कपड़ा मिल का कामकाज संभालते थे. दिसंबर में अदिति ने सिरदार कार्बनिक के प्रबंधक मंडल में शामिल होने का दावा किया. उन्होंने तीन प्रबंधकों को बोर्ड से हटाने के लिए भी नोटिस भेजा जिसमें चचेरे भाई जगदीश भी शामिल हैं. लेकिन सुधीर ने उनका दावा मानने से सरासर इनकार कर दिया.

अदिति संथानम (बाएं) और अमर मर्चेंट: हिस्से की मांग

चार्ट: बी.के. शर्मा

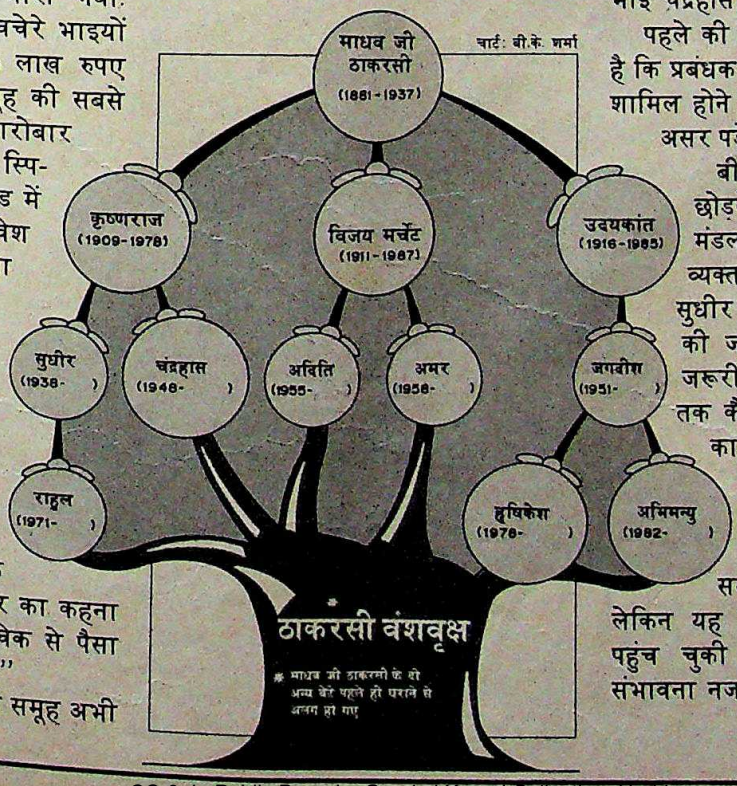

लेकिन यह झगड़ा नया नहीं है. पिछले साल जब मर्चेंट सारी कमान थामे ही हुए थे तभी कई मामलों पर विवाद उठ गया था. जैसे मध्य बंबई में सिरदार कार्बनिक का एक प्लॉट एक स्थानीय भवन निर्माता को बेच दिया गया. कहते हैं इसमें बाजार दर से कम ही पैसा लिया गया. 49 वर्षीय सुधीर ठाकरसी ने यह सौदा किया था. लेकिन बाद में कर अधिकारियों ने कंपनी को नोटिस भेजा कि वे इस जमीन को ले लेंगे. बाद में हिंदुस्तान कंपनी के वकील की अध्यक्षता में प्रबंधकों की बैठक करवाई गई. इसमें सुधीर की कार्रवाई को उचित ठहराया गया.

विवाद का दूसरा मुद्दा हिंदुस्तान की एक सहयोगी कंपनी के कर्ज के लिए सिरदार कंपनी द्वारा गारंटी लेने का है. बाद में मर्चेंट ने कहा कि सुधीर ने उन्हें गलत सूचना दी थी कि हिंदुस्तान और उसकी यह सहयोगी कंपनी दुरुस्त वित्तीय हालत में हैं. मर्चेंट के बेटे-बेटी का कहना है कि सुधीर ने घराने के एक ट्रस्ट के संरक्षकों को यह कहकर भरमा लिया कि अगर हिंदुस्तान कंपनी वाले शेयर कर्मचारियों के 31 छोटे-छोटे ट्रस्टों को बांट दिए जाएं तो ट्रस्ट संपत्तिकर से बच सकता है. इन ट्रस्टों का नियंत्रण सुधीर और उनके भाई चंद्रहास के हाथ है.

पहले की घटनाओं से संकेत मिल जाता है कि प्रबंधक मंडलों में मर्चेंट की संतानों के शामिल होने से सुधीर की स्थिति पर क्या असर पड़ेगा. पिछले अगस्त में समूह के बीमार अध्यक्ष ने अपना पद छोड़ने और अपनी बेटी को प्रबंधक मंडल में शामिल करने की इच्छा व्यक्त की थी. लगता है कि तब सुधीर का तर्क था कि संतान को बाप की जगह मिलनी ही चाहिए यह जरूरी नहीं. हालात मौजूदा विवाद तक कैसे पहुंचे इसके कई और भी कारण होंगे ही.

हां, एक बात साफ है कि अब मामला अदालत तक जाएगा. ठाकरसी बंधु समझौता भी कर सकते हैं. लेकिन यह लड़ाई अब जिस स्थिति में पहुंच चुकी है उसमें तो इसकी कोई संभावना नजर नहीं आती.

—सलिल त्रिपाठी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कंडोम निर्माण

भारतीय दबदबा

विदेशों में कंडोम की मांग बढ़ी

आने वाले कुछ हफ्तों में ही 'मेड इन इंडिया' का निशान कनाडा के लाखों युगलों के आनंद को गहराई तक प्रभावित करने जा रहा है. और अगर इस दिशा में होने वाली प्रगति आशानुकूल रही तो साल के मध्य तक आनंद की यह अनुभूति पश्चिम जर्मनी के युगलों के जीवन का भी एक हिस्सा बन जाएगी. आनंद के अलावा इसमें फायदा भी है. इस सौदे में भारत को हर साल 10 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा मिला करेगी.

एक साल पहले जब सरकारी प्रतिष्ठान हिंदुस्तान लैटेक्स लि. ने बाजार में सिर्फ 0.003 मिमी मोटा, चिकनाई-युक्त और रंगीन कंडोम 'मूड्स' पेश किया था तब यह कल्पना भी नहीं की गई थी कि 15 रुपए दर्जन कीमत वाला यह गर्भनिरोधक भारत के बजाय विदेशों में ज्यादा लोकप्रिय हो जाएगा. हाल ही में मांट्रियल की एक कंपनी ने 7.5 करोड़ कंडोम सप्लाई करने का आर्डर भेजा है. इस आर्डर के बारे में हिंदुस्तान लैटेक्स के एक अधिकारी का कहना था, "इसका श्रेय तो हर्पीज़ और एड्स के हौवे को जाता है. इसके कारण दुनिया भर में कंडोम बाजार पर विक्रेताओं का दबदबा हो गया है क्योंकि जितनी मांग है उतना उत्पादन नहीं हो पा रहा."

शायद यही कारण है कि इस भारतीय कंपनी को कनाडियन उपभोक्ता हर कंडोम के लिए 1.40 रुपए यानी भारतीय उपभोक्ता के मुकाबले 12 फीसदी ज्यादा भुगतान करने को तैयार हैं. सिर्फ यही नहीं बल्कि कंपनी को मिलने वाले आर्डरों में तब भारी वृद्धि की उम्मीद की जा रही है जब शुक्राणुनाशक लेप वाले 'मूड्स' का नया संस्करण भी बाजार में आ जाएगा. वैज्ञानिक अनुसंधान से पता चला है कि शुक्राणुनाशक रसायन एड्स के वायरस को भी नष्ट करने की क्षमता रखता है. इस कारण अब गर्भनिरोधक झिल्लियों पर इस रसायन का लेप लगाकर उसे एड्स के विरुद्ध सुरक्षात्मक ढाल के रूप में प्रयोग करने को प्रोत्साहन दिया जा रहा है.

हिंदुस्तान लैटेक्स के 'मूड्स' की इस नई अंतरराष्ट्रीय लोकप्रियता का असली राज जापान की ओकामोतो रिकेन गोमो कंपनी के सहयोग से लगाया गया वह संयंत्र है जो हर साल 32 करोड़ पतले कंडोम तैयार कर सकता है. यह कंपनी अपने 'स्किनलेस स्किन' नाम वाले कंडोम के लिए प्रसिद्ध है. जिसे दुनिया का सबसे पतली झिल्ली वाला कंडोम माना जाता है. हिंदुस्तान लैटेक्स के एक प्रवक्ता का कहना था, "0.007 मिमी से भी अधिक मोटाई वाले निरोध के मुकाबले हमारे कंडोम की मोटाई आधी से भी कम है." जापान में इस नए ब्रांड के आने के बाद एक साल में ही कंडोम की बिक्री 45 फीसदी बढ़ गई थी. लेकिन विदेशी बाजारों में येन की कीमत ज्यादा होने के कारण जापान को इसके निर्यात में कठिनाई आ रही है. जापान के अलावा इतने पतले कंडोम बनाने की व्यवस्था भारत में ही है.

एड्स के हौवे के कारण कंडोमों की मांग बेतरह बढ़ी है. भारतीय कंडोमों के निर्यात की राह में बाधा यह है कि पहले घरेलू मांग पूरी करनी है

इस हालत में निर्यात की विशाल संभावनाओं के होते हुए भी भारत इसका लाभ उठाने को उत्सुक नहीं है क्योंकि भारत में ही इसकी मांग बहुत है. इस बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है, "पहले के मुकाबले अब हमारा परिवार कल्याण कार्यक्रम कंडोम पर कहीं अधिक निर्भर हो चुका है इसलिए हम अपने यहां के कारखानों में उत्पादित सारे का सारा माल खरीद लेना चाहते हैं." हालत यह है कि हिंदुस्तान लैटेक्स के अलावा मद्रास की लंदन रबर कंपनी और औरंगाबाद की लोरकॉम कंपनी द्वारा हर साल तैयार किए जाने वाले 110 करोड़ कंडोमों में से अधिकांश सरकार खरीदती है.

ये कंडोम या तो परिवार कल्याण कार्यक्रम या फिर हिंदुस्तान लीवर, आइटीसी, ब्रुकबांड और लिप्टन जैसी बड़ी कंपनियों के माध्यम से वितरित किए जा रहे हैं. बाजार अनुमानों के अनुसार भारत में 1991 में 158.4 करोड़ कंडोमों की मांग होगी जिसे उत्पादन बढ़ाए बिना पूरा नहीं किया जा सकता. इसीलिए सरकार निर्यात के मामले में बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं है.

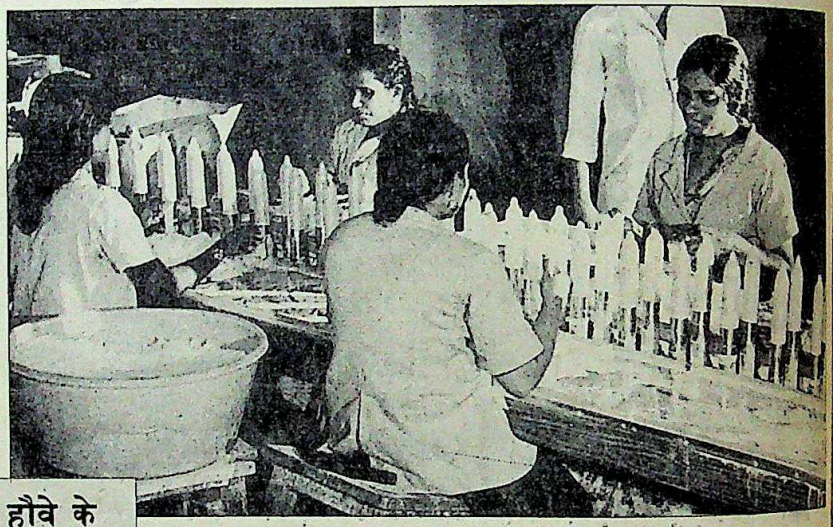

कंडोम की इलेक्ट्रानिक जांच: ऊंचा स्तर

बल्कि सचाई तो यह है कि भारतीय बाजार को गर्भनिरोधकों से पाट देने की इच्छुक भारत सरकार ने भारतीय निर्यातकों के विरोध के बावजूद कंडोम को आसान आयात वाली ओपन जनरल लाइसेंस सूची में रखा हुआ है. 1977 में रंगीन कंडोम के आयात को सरल बना दिया गया था क्योंकि तब इसका उत्पादन भारत में नहीं होता था लेकिन अब भारतीय निर्माताओं की शिकायत है कि भारतीय कंडोमों के मुकाबले घटिया होने के बावजूद आयातित कंडोम अपनी उत्तेजक पैकिंग और 'डू इट', 'हॉट' और 'स्वीटी' जैसे उत्तेजक नामों के कारण धड़ल्ले से बिक रहे हैं. लगता है कि जब तक सरकार घरेलू उत्पादकों को भी इसी तरह के उत्तेजक पैकिंग इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देती तब तक उन्हें निर्यात का सहारा लेना होगा. इसके लिए अब तक एड्स का डर उन्हें सहारा दिए ही हुए है.

—शेखर गुप्ता

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शेयर बाजार

बदलाव का रुख

सुस्ती का मौसम खत्म

शेयरों के भाव जब चढ़ते हैं तो यह सब के लिए खुशखबरी होती है. पर भावों का गिरना क्या सदा बुरी खबर लाता है? शायद नहीं. पहले के दो हफ्तों में ऊपर चढ़ रहे शेयर पिछले पखवाड़े जब एकदम गिरने लगे तब भी निवेशक उम्मीद बांधे हुए थे कि शेयर बाजार में गिरावट का सबसे खराब मौसम खत्म हो गया है.

निश्चित ही इस खुशी की कई वजहें भी हैं. सूखे के बावजूद कंपनियों की दशा बहुत बुरी नहीं थी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और केनरा बैंक द्वारा जारी बांडों पर निवेशकों की अच्छी प्रतिक्रिया इस बात का संकेत थी कि शेयर बाजार में उनका भरोसा फिर लौट आया है. यह बदलाव लोहे और एल्यूमिनियम की कीमतें बढ़ने तथा लंबे समय से चर्चा में चल रही ऑटोमोबाइल नीति को अंततः अंतिम रूप देने के बाद हुआ है.

चार्ट: बी.के. शर्मा

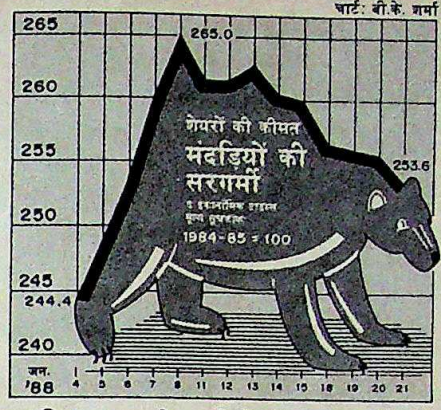

इसलिए बहुत से उद्योगों में उत्पादकों को अच्छी खबर की उम्मीद है. इसका नतीजा यह हुआ कि जितने शेयरों के भाव गिरे उतने ही शेयरों में उछाल आया और उनमें शेयर मूल्य सूचकांक के शिखर पर पहुंचने की प्रवृत्ति दिखाई देने लगी.

फिर भी बजट से पहले अनिश्चितता का तो रिवाज रहता ही आया है. इसके साथ ही पिछले पखवाड़े वित्तमंत्री नारायणदत्त तिवारी को हटाए जाने की अटकलों से भी कुछ घबराहट थी. बजट के आसार अच्छे नहीं लग रहे हैं. भारी टैक्स लगाए जाने का अंदेशा हो गया है. इसलिए निवेशक शेयरों का सबसे खराब मौसम समाप्त होने या शेयरों में नई गिरावट का इंतजार कर रहे हैं.

इस वजह से बाजार में अनिश्चितता है. पिछले पखवाड़े जब कई निवेशकों ने शेयरों की उछाल से होने वाला फायदा जेब में डाल लिया तो कई शेयरों के भाव गिर गए. और 'द इकॉनॉमिक्स टाइम्स' का शेयर मूल्य सूचकांक इस साल 3 जनवरी '88 के अधिकतम अंक 265.0 से एक पखवाड़े बाद ही गिरकर 253.6 पर आ गया. कुछ वित्तीय संस्थानों द्वारा बिकवाली के कारण भी अनिश्चितता और भी बढ़ गई.

फिर भी सभी की राय है कि सुस्ती का मौसम खत्म हो गया है और अब अच्छा वक्त आएगा. निवेशकों को उम्मीद है कि यदि बजट में कोई अच्छी खबर न भी रहे, तो भी उन्हें कुछ आकर्षक प्रोत्साहन जरूर मिल जाएगा.

वजह चाहे जो भी हो पर इतना तय है कि अब 1987 जैसी निराशा नहीं रही है. हालांकि बाजार में वैसा उत्साह भी नहीं दिख रहा, जैसा दिखना चाहिए और आने वाले बजट के मद्देनजर वैसा उत्साही माहौल लौटने की उम्मीद भी नहीं दीखती. पर बाजार का रुख तेजी से बदल रहा है.

जमा स्टॉक

	1988 ऊंचा	1988 नीचा	1988 बंद 21.1.88	पखवाड़े में स्टॉक की स्थिति
अशोक लेलैंड	36.50	32.25	32.50	3.00 —
एसोसिएटेड सीमेंट	180.00	152.00	164.00	4.00 +
एटलस कोप्को	63.50	51.00	56.00	2.00 +
एशियन पेन्टस	169.00	147.50	155.00	6.25 —
बजाज ऑटो	520.00	452.50	463.75	21.25 —
बड़ौदा रेयॉन	168.00	145.00	152.50	7.50 —
बाटा इंडिया	71.50	65.50	67.75	1.25 —
बेयर	320.00	305.00	305.00	15.00 —
भारत फोर्ज	118.00	101.00	107.00	9.00 —
बिरला जूट	44.00	39.80	40.50	2.70 —
ब्लो प्लास्ट	125.00	105.00	112.50	12.50 —
बॉम्बे डाइंग	121.50	94.00	116.00	5.50 +
बुक बांड	87.00	82.50	83.50	1.50 —
बिटानिया इंडिया	109.00	93.00	97.00	5.00 —
सीएट टायर्स	88.00	82.00	86.50	2.00 +
सेंचुरी एंका	1250.00	1100.00	1190.00	8.00 +
क्लोराइड इंडिया	80.50	75.50	78.00	—
सिमुरगिया	70.00	61.00	65.00	5.00 —
कोलगेट	220.00	192.50	203.75	5.25 —
डीसीएम	38.25	31.00	35.75	1.75 —
डनलप	83.00	77.50	80.50	1.50 +
एस्काट्स	44.00	40.00	41.75	0.25 +
फिनोलेक्स केबिल्स	380.00	311.25	347.50	17.50 —
फूड स्पेशिलिटीज	142.00	129.00	133.00	2.00 —
गरवारे नाइलोन	30.00	20.00	25.00	4.00 +
जी.ई. शिपिंग	26.35	20.50	24.35	3.50 +
गुजरात स्टेट फर्टि.	118.00	86.50	112.00	8.50 +
ग्रासिम इंडिया	104.75	93.00	95.50	7.50 —
हिंदु. एल्यूमिनियम	139.00	116.00	124.00	—
हिंदुस्तान कोकोआ	215.00	188.75	200.00	5.00 —
हिंदुस्तान लीवर	81.00	70.00	74.00	3.00 —
हिंदुस्तान मोटर्स	25.00	21.90	22.80	1.40 —
हिंदुस्तान डॉर	212.50	172.50	177.50	27.50 —
आई.ई.एल.	43.75	39.90	40.00	1.50 —
भारतीय होटल	120.50	100.00	102.50	2.50 —

	1988 ऊंचा	1988 नीचा	1988 बंद 21.1.88	पखवाड़े में स्टॉक की स्थिति
इंडियन आर्गेनिक	23.00	19.00	19.75	2.25 —
इंडियन रेयॉन	58.00	51.50	52.00	3.00 —
इंड्राल	223.75	185.00	197.00	26.25 —
इंगरसॉल-रैंड	335.00	290.00	295.00	37.50 —
आई.टी.सी.	39.75	32.75	32.75	5.75 —
जे.के. सिंथेटिक्स	69.00	60.50	62.00	4.50 —
काइनेटिक इंजी.	185.00	170.00	177.50	1.25 +
किर्लोस्कर क्युमिंस	54.00	48.00	51.00	3.00 —
केएसबी पम्प	425.00	372.50	386.25	12.50 —
लारसन-टुब्रो	95.50	77.00	91.00	10.50 +
लिप्टन	67.00	59.00	60.00	2.00 —
लोहिया-मशीन्स	13.50	10.00	11.00	2.50 —
महिंद्रा-महिंद्रा	63.00	52.00	58.50	3.50 +
मैक्डोवेल	83.50	73.00	78.00	6.00 —
मोटर इंडस्ट्रीज	587.50	490.00	540.00	2.50 +
मुकुंद आयरन	85.00	76.00	80.00	0.50 +
नेशनल आर्गेनिक	525.00	435.00	470.00	20.00 —
निरलॉन	8.75	5.00	5.00	3.25 —
ओरके सिल्क मिल्स	30.00	23.00	26.00	0.50 +
पेइको इलेक्ट्रॉनिक्स	33.75	29.25	29.50	3.00 —
ओसवाल आग्रो	134.50	118.50	119.00	7.00 —
ओटिस एलिवेटर	215.00	190.00	200.00	15.00 —
प्रीमियर ऑटो	31.00	24.50	27.25	1.25 +
रैनबेक्सी	102.50	78.00	89.00	11.00 —
रेमंड	96.00	88.00	91.00	1.00 —
शॉ वैलेस	132.00	116.00	122.00	2.00 —
रिलायंस इंडस्ट्रीज	117.00	103.00	106.00	10.00 —
रिचर्डसन हिंद	305.00	270.00	275.00	29.00 —
श्रीराम फाइबर्स	42.75	36.50	39.00	2.00 —
सैंडोज	1250.00	1058.00	1200.00	48.00 —
सीमेन्स इंडिया	80.00	71.00	76.00	2.00 +
स्पिक	37.00	28.50	33.75	0.50 +
टाटा स्टील	685.00	616.00	648.75	13.75 —
टेल्को	400.00	343.00	375.00	32.00 +
विम्को	24.00	20.00	21.50	0.75 +

भारतीय रुपए का मूल्य

देश	मुद्रा	इकाई	बिक्री मूल्य (रुपए में)	क्रय मूल्य (रुपए में)
आस्ट्रेलिया	डालर	1	9.3508	9.2512
आस्ट्रिया	शिलिंग	1	1.1221	1.1099
बहरीन	दीनार	1	35.1280	35.0011
बांग्लादेश	टका	100	43.3310	43.2118
कनाडा	डालर	1	10.1850	10.0759
डेनमार्क	क्रोनर	1	2.0554	2.0333
मिस्र	पौंड	1	9.5113	9.4331
फ्रांस	फ्रैंक	1	2.3446	2.3121
हांगकांग	डालर	1	1.6780	1.6608
इंडोनेशिया	रुपिया	100	0.0080	0.0079
ईरान	रियाल	100	19.3110	19.2718
इटली	लीरा	100	1.0000	0.9700
जापान	येन	100	10.3500	10.1000
केन्या	शिलिंग	1	0.7930	0.7710
कुवैत	दीनार	1	47.8132	47.7310
मलेशिया	डालर	1	5.1284	5.0735
मारीशस	रुपया	1	1.0530	1.0000
नेपाल	रुपया	1	0.6190	0.6000
हालैंड	गिल्डर	1	7.0244	6.9508
पाकिस्तान	रुपया	1	0.7700	0.7500
सिंगापुर	डालर	1	6.4619	6.3913
स्पेन	पेसो	1	0.1157	0.1003
श्रीलंका	रुपया	1	0.4330	0.4120
स्वीडन	क्रोनर	1	2.1895	2.1659
स्विट्जरलैंड	स्विस फ्रैंक	1	9.7229	9.6226
तंजानिया	शिलिंग	1	0.1623	0.1590
थाईलैंड	बहत्त	100	52.8230	51.9220
ब्रिटेन	पौंड	1	23.4750	23.3425
सं. राज्य अमेरिका	डालर	1	13.0725	12.9425
सं. अरब अमीरात	दिरहाम	1	3.5704	3.5218
सोवियत संघ	रूबल	1	18.9220	17.3130
पश्चिम जर्मनी	जर्मन मार्क	1	8.0000	7.8003

स्रोत—बैंक ऑफ टोक्यो, नई दिल्ली, 25.1.88

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्राणलाल भोगीलाल

कला और कारों के शौकीन

इस 'अंतिम महाराजा' के ठाटबाट और शान निराली ही है

बंबई के मालाबार हिल इलाके में लाल पत्थर के कंगूरों वाले किलेनुमा बंगले के सामने आकर एक लंबी और भूरे रंग की रॉल्स रॉयस फैंटम-6 कार आकर मुड़ती है और दूसरी गाड़ियां जैसे सहमकर रास्ता दे देती हैं. लोग उसे घूरकर देखते हैं. क्रोम की बनी उसकी झंझरी सूरज की रोशनी में चमक उठती है. गाड़ी घरघराकर रुक जाती है. ऊंचे-ऊंचे दरवाजे इस नई रॉल्स रॉयस के लिए खुलते हैं. सामने के अहाते में पहले से ही कई रॉल्स रॉयस और बेंटले कारें करीने से खड़ी हैं. 1975 मॉडल की इस रॉल्स रॉयस में से नाटे कद और सफेद बालों वाला एक आदमी उतरकर तिमंजिली इमारत में लुप्त हो जाता है. आसपास की बहुमंजिली इमारतों से हर रोज यह दृश्य देखने वाले लोग समझ जाते हैं कि 50 वर्षीय प्राणलाल भोगीलाल घर लौट आए हैं. घर क्या, यह कहिए कि पुरानी और बेशकीमती कारों तथा दूसरी अमूल्य धरहरों का खजाना.

बहुत कम ही लोगों को इस घर में आने और यहां की कीमती कलाकृतियों और पुरानी चीजों या उसके रंगीन शीशों की खिड़कियों को देखने का मौका या न्यौता मिल पाता है. लेकिन उनकी पुरानी कारों की चर्चा हर जगह है. यहां तक कि मारुति, एंबेसडर और फिएट कारों की अनंत कतारों से ऊबे ट्रैफिक सिपाहियों के आगे से भी जब भोगीलाल अपनी पुरानी रॉल्स रॉयस, बेंटले या लागोंडा कार पर सवार होकर निकलते हैं तो उनके चेहरे की बोरियत भी दूर हो जाती है. उन्हें भी शायद ट्रैफिक सिपाहियों की उतनी ही सलामियां मिलती हैं जितनी उनके विख्यात पड़ोसी, राज्यपाल को मिलती हैं.

दासकोट नामक उनका बंगला राजभवन के बिलकुल सामने है. उसकी तुलना में राजभवन मड़ई सरीखा दिखता है. कई राज्यपाल भी कह चुके हैं कि असली राजभवन तो दासकोट ही है. ऐसे राज्यपाल भी रहे हैं जो अपने अतिथियों पर रौब गांठने के लिए उनकी रॉल्स रॉयस उधार लेते रहे हैं.

भोगीलाल बंबई के अद्भुत संग्राहक हैं. नई रॉल्स रॉयस जुटाने में जो ख्याति रजनीश ने हासिल की, वही पुरानी कारों के मामले में उन्हें मिली है. रजनीश को तो उनके कुछ अमेरिकी चेलों ने 93 रॉल्स रॉयस का मालिक बनाकर गिनीज बुक में शामिल करा दिया. पर भोगीलाल ने अपने दम पर

सभी फोटो: प्रशांत पंजियार

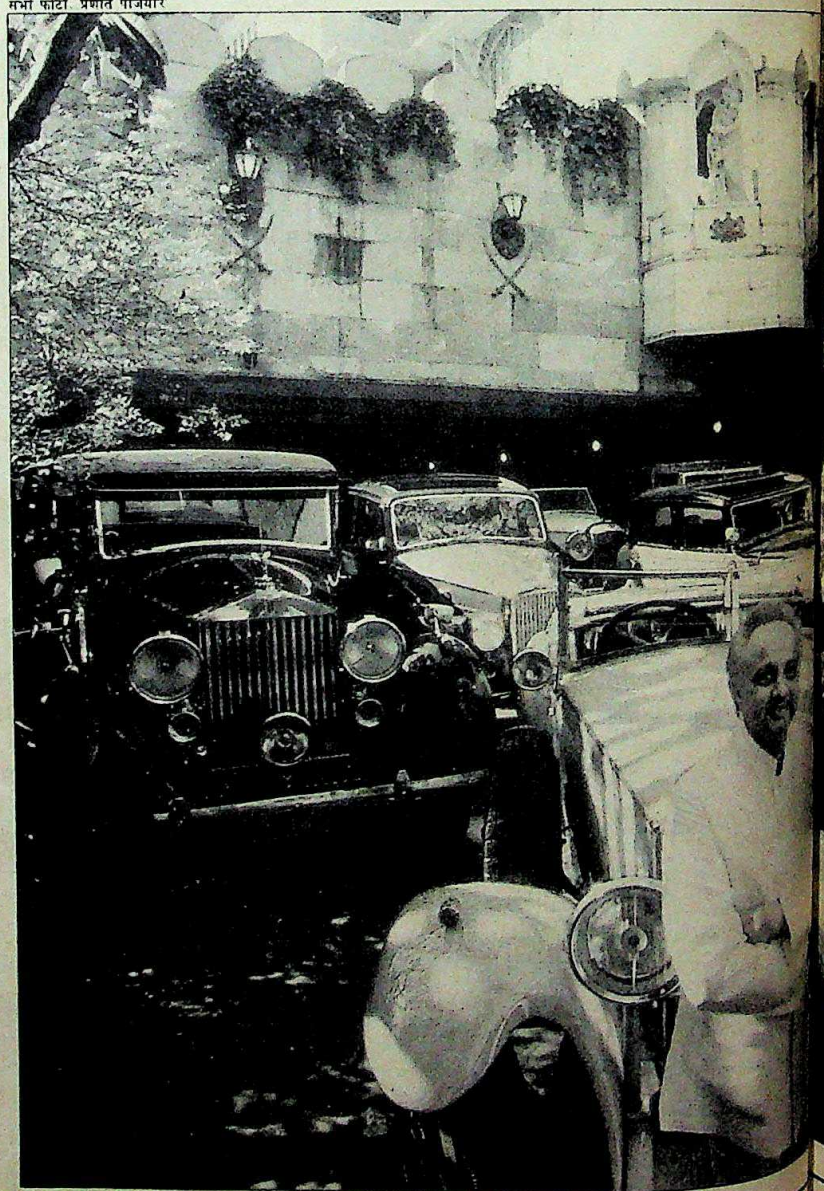

1931 बेंटले दुर्गा

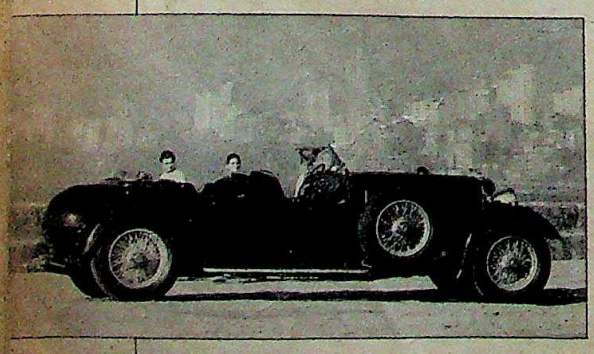

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

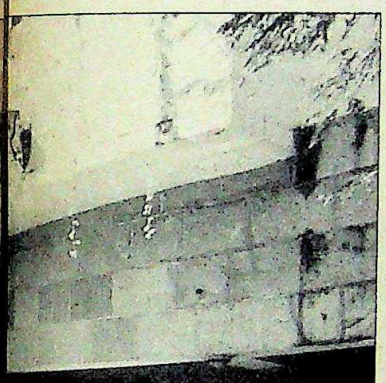

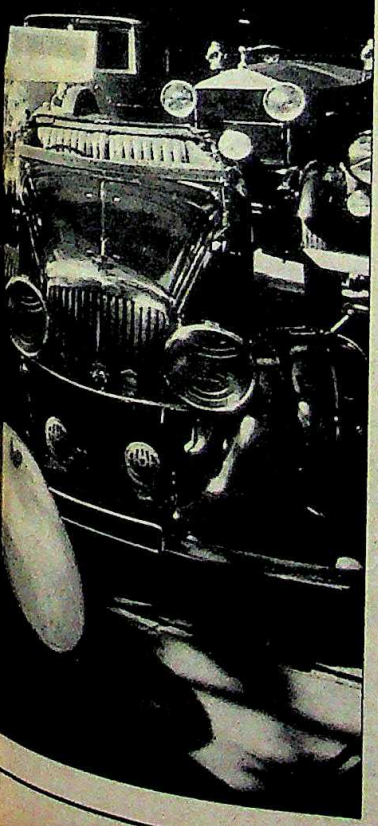

पुरानी कारों के संग्रहकर्ता भोगीलाल (बाएं) ; और उनकी बेटी: महंगा शौक

1987 में इस रिकार्ड बुक में नाम दर्ज कराया. उन्हें दुनिया का सबसे बड़े निजी गराज का मालिक माना गया. वडोदरा के निकट बिलिमोरा में उनके दोमंजिले गराज में 176 कारें हैं. वैसे उनका संग्रह अब दो सौ कारों के करीब पहुंच रहा है. इनमें से 36 तो रॉल्स रॉयस या बेंटले कारें हैं (बेंटले भी रॉल्स रॉयस कंपनी की ही बनी हुई है पर उसमें वह खास झंझरी नहीं लगी है).

पर भोगीलाल की पुरानी कारें तो उनकी कलात्मक, खूबसूरत और प्राचीन चीजों के खजाने का एक हिस्सा मात्र हैं. इससे भी अधिक बेशकीमती तो उनका कला संग्रह है जिसमें करीब 500 भारतीय चित्र, लगभग 2000 कांसे की मूर्तियां और कुछ ऐसी प्राचीनतम मूर्तियां हैं जो संग्रहालयों में भी नहीं मिलतीं. लेकिन उनका 'अलीबाबा का यह खजाना' किसी तिजोरी में बंद नहीं है. यह दसकोट की तीन मंजिलों और परिवार के दूसरे मकानों में जगह-जगह पर रखा हुआ है.

भोगीलाल इसी खजाने में मस्त रहते हैं, इसी के आभामंडल में सांस लेते हैं. वे अपना नाम 'दास' प्राणलाल भोगीलाल लिखते हैं. और जब से उनके किसी पूर्वज ने अपनी सारी संपत्ति अपने गृह देवता को अर्पण कर दी तभी से परिवार के हर सदस्य के नाम के आगे दास (सेवक) शब्द जुड़ गया.

वे कहा करते हैं कि संख्या, रिकार्ड और पुरस्कारों का उनके लिए कोई महत्व नहीं है. पुरानी कारों की दुनिया के पांच बड़े संग्रहकर्ताओं में वे भी एक हैं. वे कहते हैं, "मैं बड़ी आसानी से 100 कारें और जुटा सकता हूं पर फिर भारी भीड़-भड़क्का हो जाएगा. मैं दुनिया की सबसे (पुरानी) महंगी कार भी खरीद सकता हूं. लेकिन अगर वह मुझे कलात्मक नहीं लगी तो नहीं खरीदूंगा."

भोगीलाल की कारों की खूबसूरती का कोई सानी नहीं है. इन कारों को कभी बेचने के लिए नहीं रखा गया और पुरानी कारों के सौदागरों को इनके पास फटकने भी नहीं दिया जाता. इसलिए इस संग्रह की कीमत आंकना मुश्किल है. वैसे भी भारत से पुरानी कारों के निर्यात पर 1972 से रोक लगी हुई है. इसलिए कारों के अंतरराष्ट्रीय सौदागर यहां कम ही आते हैं.

उनके संग्रह में सबसे दुर्लभ हैं पीछे से पिचकी बनावट वाली 20/25 कन्वर्टिबल रॉल्स (जिसकी छत गिराई जा सकती है) और 1931 मॉडल की आठ लीटर वाली शक्तिशाली बेंटले कन्वर्टिबल. आश्चर्य नहीं कि ताकत और ऊर्जा देखकर ही भोगीलाल ने इसको दुर्गा नाम दिया था. इस मॉडल की 50 से भी कम कारें आज दुनिया में रह गई हैं. 57 वर्ष पुरानी यह कार 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार मजे से पकड़ लेती है.

लाल रंग वाली रॉल्स कन्वर्टिबल, जिसका आर्डर मंडी के महाराजा ने दिया था, अब चामुंडा नाम से जानी जाती है. 'दुनिया की सबसे खूबसूरत रॉल्स रॉयस में से एक' इस दो सीटों वाली कार को चार सीटों वाली बनाया और दो सीटों को बड़े आयोजनों के लिए ऊंचा भी उठाया जा सकता है. 1937 मॉडल की गहरे नीले रंग वाली रॉल्स रॉयस फैंटम-3 को इसके 'राजसी ठाट' के कारण 'शहंशाह' नाम दिया गया है. इसके मूल मालिक छोटा उदयपुर के महाराजा थे.

इस संग्रह में 1937 मॉडल की ही एक रॉल्स, चमकीले भूरे रंग की सेडांका डी विले का भी खास स्थान है. इसका नाम रखा गया है 'पुष्पक'. इसे भोगीलाल की एकमात्र संतान चामुंडेश्वरी को उसके पहले जन्मदिन पर उसके दादा ने उपहार में दिया था. इस प्रकार वह रॉल्स रॉयस की सबसे कम उम्र वाली मालकिन बन गई.

वैसे इस संग्रह का सबसे अनूठा 'रत्न' 1923 मॉडल की रॉल्स रॉयस सिल्वर घोस्ट है. विक्टोरिया की तरह बनी इस कार में एक तरफ गैस लैंप रखने की व्यवस्था भी है. लेकिन हार्न की जगह इसमें फर्श पर घंटी लगी हुई है. दुनिया में इस तरह की यह दूसरी कार है. इसका उपयोग मैसूर के महाराजा अपने महल के बगीचे में चक्कर लगाने के लिए करते थे.

भोगीलाल की नवीनतम रॉल्स, 1975 मॉडल की फैंटम-6 का नाम 'बर्किंघम' है. यह

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रॉल्स रॉयस फैंटम II शहंशाह

कार महारानी एलिजाबेथ (द्वितीय) की भारत यात्रा के लिए मंगाई गई थी. लागोंडा कारों के एक जोड़े को 'सीजर' और 'क्लियोपेट्रा' नाम दिया गया है. तीसरे को 'मार्क एंथनी' का नाम दिया जाना है. 1947 मॉडल की बेंटले मार्क-4 को उसके 'डिजाइन की खूबसूरती के कारण' 'माइकेलएंजिलो' नाम दे दिया गया है. भोगीलाल के एक दाढ़ी वाले दोस्त बनर्जी ने 1926 मॉडल की जो लागोंडा उन्हें भेंट में दी उसे 'दाढ़ीबेन' नाम दिया गया है.

संग्रह की सभी पुरानी रॉल्स अपनी तरह की अकेली ही हैं. दूसरे विश्वयुद्ध तक रॉल्स रॉयस कंपनी कार की बॉडी नहीं बनाती थी. आप रॉल्स रॉयस का इंजन और चेसिस खरीदिए और अपने पसंद की बॉडी कहीं बाहर से बनवा लीजिए. कोई ऐसी मांग नहीं थी जो पूरी न हो सके. नाभा के महाराजा ने 1911 मॉडल की अपनी रॉल्स के बोनट पर चांदी की मीनाकारी करा रखी थी. इसे वे 'ताजमहल' कहा करते थे. वह रॉल्स कार भारत में सबसे पुरानी है और अब इसे भोगीलाल को बेचने की पेशकश की गई है.

यह अद्भुत संग्रह शुरू कैसे हुआ और दुनिया का सबसे बड़ा और अच्छा संग्रह कैसे बन गया? निश्चित रूप से यह अकेले भोगीलाल का काम नहीं. इस मामले में उनकी दादी आदित्य बाई सबसे आगे थीं. वे आजादी पूर्व भारत में एक बहुत बड़े जमींदार परिवार की मुखिया थीं. उन्हें जो भी चीज पंसद आ जाती, वे खरीद लेतीं. इससे भी बड़ी बात यह है कि उनके यहां पुरानी कारों को कभी बेचा नहीं गया.

भोगीलाल के दिल की मलिका बन जाने वाली एक कार है—1939 मॉडल की एक पैकार्ड, जिस पर चढ़कर वे रोज स्कूल जाया करते थे. उन्हें यह कार पसंद थी तो उनके पड़ोसी, अर्थात गवर्नर को भी यह भा गई जो इसे वायसराय के इस्तेमाल के लिए मांगना चाहते थे. भोगीलाल बताते हैं, "लेकिन हमने यह कार बिलिमोरा में छिपा दी जहां गवर्नर उसे देख न सकें. हमने गवर्नर से कहा कि कार बेच दी गई है. आजादी के बाद हमने जब इसे बाहर निकाला तो परिवार का हर सदस्य इस पर ललचा रहा था."

मजेदार बात यह है कि भोगीलाल को कारों का 'दीवाना' नहीं कहा जा सकता. "मैं कारों के प्रति उनके कार होने भर से आकर्षित नहीं हूं. मेरा पहला प्रेम तो कला से है, पर कुछ कारों की सुंदरता मुझे बहुत आकर्षित करती है. मैं उन्हें किसी कलाकृति की तरह ही मानता हूं." उनका आकर्षण आधुनिक कारों के प्रति अधिक नहीं है. 1930 के दशक में बनी लंबी हुड और नीचे तक झुकी कारें उन्हें खास पसंद हैं.

'विंटेज ऐंड क्लासिक कार क्लब ऑफ इंडिया' के वर्तमान अध्यक्ष भोगीलाल अपनी कारों को कभी भी पुरानी कारों की प्रतियोगिता में शामिल नहीं करते.

वे आम तौर पर अपने दोस्तों के यहां शादी या किसी बड़े आदमी को हवाई अड्डे से लेने के लिए मांगने पर अपनी रॉल्स दे देते हैं. लेकिन वे इस बात के प्रति जरूर सावधानी बरतते हैं कि कारों का उपयोग किस तरह किया जाता है. "हर कोई कम से कम एक बार रॉल्स में बैठना चाहता है पर मैं कारों की दुर्दशा हो, यह मुझे पसंद नहीं उनकी अपनी शान है. अगर आप खुली रॉल्स पर चल रहे हों तो आपको कायदे के कपड़े पहने होना चाहिए और पता होना चाहिए कि बैठने का सलीका क्या है." उन्होंने अब तक कोई कार कभी नहीं बेची. हां, आगे न बेचने की शर्त पर कुछ कारें जरूर लोगों को दी हैं. प्रायः हर बार ये गाड़ियां छह महीने के अंदर ही लौटा दी गईं क्योंकि नए मालिक उनकी 'मांग' पूरी नहीं कर पाते थे. और ये मांगें अच्छा-खासा सिरदर्द होती हैं जिन्हें पूरा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

करने में काफी समय और धन बरबाद होता है. 350 फीसदी उत्पादकर देने के बाद इसके छह टायरों का नया सेट 'मात्र' 45 हजार रुपए में आता है. इसके पुर्जे पाना तो और भी टेढ़ी खीर है. लेकिन भोगीलाल अपनी इंजीनियरिंग इकाई में ये पुर्जे बनवा लेते हैं. अपनी कारों की फौज चकाचक रखने के लिए उन्होंने 20 ड्राइवरों और मिस्त्रियों की टोली और एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर तैनात कर रखा है. इसके बाद भी गंभीर मुश्किलें पैदा हो सकती हैं. उनके मिस्त्री मेबैक कार का गियर बाक्स देखकर उलझन में पड़ गए. इसमें आगे के सात और पीछे के तीन गियर हैं. वे अभी भी इसे ठीक ढंग से बैठा पाने की कोशिश कर रहे हैं.

कोई इतनी शक्तिशाली गाड़ियों का मालिक हो और तेज रफ्तार से चलना पसंद न करे, यह मुमकिन नहीं. भोगीलाल भी यह ललक रोक नहीं पाते. 12 सिलिंडर वाली चामुंडा या 1932 मॉडल की इंविक्टा पर बैठकर उनका मन वश में नहीं रहता.

दासकोट के अंदर: खजाना

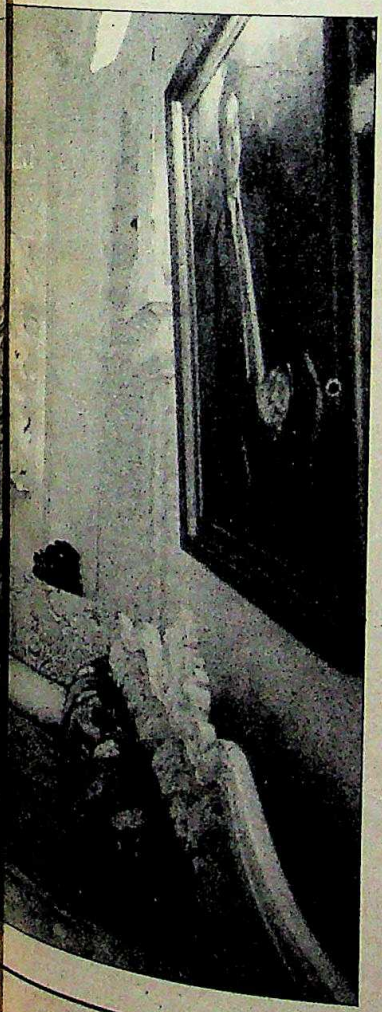

भोगीलाल को कई गाड़ियां तो उन लोगों ने उपहार में दी हैं जो उनकी पर्याप्त देखरेख नहीं कर पाते थे या उन्हें भरोसा था कि भोगीलाल उनकी गाड़ियों की बेहतर हिफाजत कर सकते हैं. कुछ वसीयतें तो बहुत ही अजीब हैं. कैंसर से मरी एक परिचित महिला ने अपनी वसीयत में लिखा कि उन्होंने 1964 मॉडल की अपनी स्टैंडर्ड हेराल्ड कार की हिफाजत भी उसी तरह से की जिस तरह से भोगीलाल अपनी रॉल्स रॉयस गाड़ियों की करते हैं. आगे लिखा है कि अगर यह कार भी भोगीलाल की रॉल्स रॉयस के साथ रखी जाए तो उनकी आत्मा को बहुत शांति मिलेगी.

कार के कद्रदानों के लिए अगर भोगीलाल आदर्श हैं तो कला प्रेमियों के लिए एक बड़े पारखी भी. पर ये दो चीजें तो उस पूरी जीवन शैली का एक अंश भर है जिसके कारण एक पत्रिका ने उन्हें 'अंतिम महाराजा' कहा था. उनकी अधिकांश कलाकृतियां कला के अंतरराष्ट्रीय संग्रहकर्ताओं की सूची में दर्ज हैं. उनके भोजन कक्ष के दर्जन भर से अधिक कांसे के दीपस्तंभ रूस के जार के संग्रह से आए हैं. उनके यहां आने वाले अंतरराष्ट्रीय सौदागर खाली हाथ ही लौट जाते हैं. एक अमेरिकी सौदागर ने तारे की आकृति वाले एक 'लालिक दीपस्तंभ' को 38 हजार डालर रुपए में देना चाहा था. पर वह यह देखकर दंग रह गया कि भोगीलाल के घर में ऐसे छह दीपस्तंभ हैं और उनका पूरा कमरा 'लालिक' कलाकृतियों से भरा है.

रॉल्स रॉयस 20/25 चामुंडा

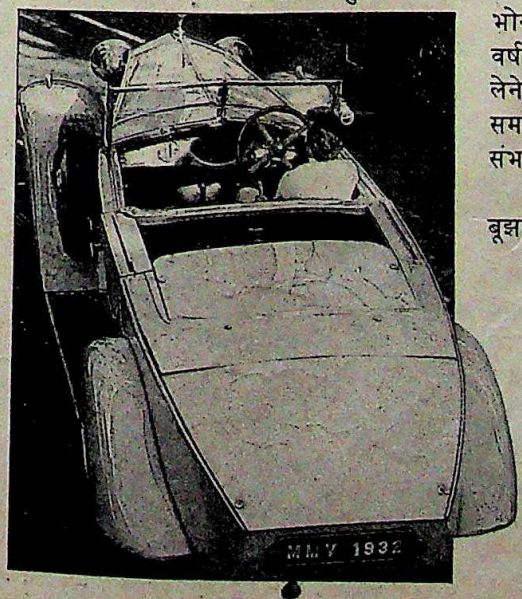

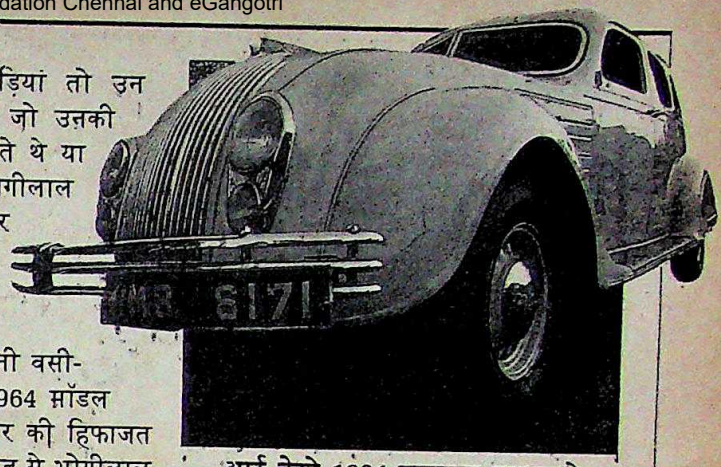

आर्ट डेको 1934 क्राइस्टर एअरफ्लो

भोगीलाल, उनकी पत्नी और बेटी मालाबार हिल वाले मकान की अलग-अलग मंजिल में रहते हैं. बंबई का यह सबसे महंगा घर है. उनकी हर इच्छा को पूरी करने के लिए 50-60 नौकरों की पूरी फौज लगी रहती है. भोगीलाल परिवार पक्के अभिजात नियमों के तहत दैनंदिन जीवन जीता है जिसमें हर मौके पर उसी के अनुरूप पोशाक पहनना भी शामिल है.

आज तक इस परिवार का कोई भी सदस्य किसी चीज के लिए दुकान पर नहीं गया है. "पीढ़ियों से दुकानें ही हमारे यहां उठकर आ जाती हैं." परिवार की परंपराओं के अनुसार भोगीलाल, उनकी पत्नी और बेटी एक ही इलाके में उसी कार या विमान से दोबारा नहीं जाते. 10 साल की बेटी, चामु कभी भी स्कूल नहीं गई. उसे कला और जीवन की दूसरी बारीकियां बताने के लिए शिक्षकों की पूरी जमात घर पर ही आ जाती है. तीन वर्ष की उम्र से ही वह विशेष आमंत्रित के तौर पर 100 करोड़ रुपए कारोबार वाली दास समूह की कंपनियों के प्रबंधक मंडलों की अधिकांश बैठकों में हिस्सा लेती आई है. भोगीलाल कहते हैं, "हम चाहते हैं कि 12 वर्ष की होने तक वह कामकाज में दिलचस्पी लेने लगे. 15 वर्ष की उम्र तक व्यवसाय को समझ ले और 18 वर्ष पर उसमें कामकाज संभालने का आत्मविश्वास आ जाए."

भोगीलाल कहते हैं कि उन्होंने जान-बूझकर कम रफ्तार से प्रगति करने का फैसला किया है. वे कहते हैं, "मैं क्यों वे तनाव झेलूं या अपनी संपत्ति का गुलाम बन जाऊं. मैं तो खुद को इस संपत्ति का संरक्षक भर मानता हूं." और वे अपनी कारों पर नजर डालें या कलाकृतियों पर, मकान देखें या फैक्टरियों को, हर जगह यही समृद्धि दिखती है. आखिर उन्हें यों ही तो 'आखिरी महाराजा' नहीं कहा जाता.

—रमिंदर सिंह, बंबई में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आज का शॉ वॉलस

जहाँ दृष्टि बदले सृष्टि में

शॉ वॉलेस उद्यम के विविध आयाम।

गोंद, जिलेटिन, खमीर, शराब, चाय, जहाजरानी, खेती के साधन, औद्योगिक रसायन, जूते, डिटर्जेन्ट्स और शृंगार प्रसाधन...

शताधिक वर्षों में पनपी गतिविधियों का प्रकाशपुंज।

अब, छाबरिया समूह का एक अंश बनकर नई नई सीमाओं की ओर अग्रसर।

तेल निकासी और उपकरण, भूकंप सम्बन्धी सर्वेक्षण, टायर, स्थावर संपदा विकास, जैव तकनीक।

उद्यम की दुनिया में एक नये युग की ओर बढ़ते कदम।

शॉ वॉलेस यानि-
कल्पना. हिम्मत. कामयाबी

Shaw Wallace

छाबरिया समूह का सदस्य
वॉलेस हाउस, ४, बैंकशाल स्ट्रीट,
कलकत्ता ७०० ००१

TSA-SW-C-1-R

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

एनआरआइ फिल्में

पोस्टर उखड़ गए

नए कानून से आयातक निराश

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को यह समझने में तीन साल लग गए कि आप्रवासी भारतीय फिल्म आयात योजना बेकार थी. 1984 में बनाई गई इस योजना के तहत किसी भी आप्रवासी भारतीय को 15,000 डॉलर (1.97 लाख रुपए) मार्ग नियंत्रण फीस फिल्म विकास निगम को अदा करके विदेशी फिल्मों का आयात करने की छूट थी. उसके बाद से ऐसी करीब 274 फिल्में आयात की गईं. इनमें से ज्यादातर या तो अश्लील या मारधाड़ से भरपूर थीं.

दूसरे दर्जे की इन फिल्मों की अंधाधुंध कामयाबी से मुख्य भाषायी व्यावसायिक सिनेमा के लिए, खासकर दक्षिण में, खतरा पैदा हो गया. आखिरकार अखबारों, महिला संगठनों, सेंसर बोर्डों और भारतीय फिल्म निर्माताओं द्वारा इन फिल्मों की आलोचना के कारण देर से ही सही, सरकार की नींद टूटी और उसने विदेशी फिल्मों के आयात के लिए नए नियम बनाने का फैसला किया.

हाल में मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा फिल्मी प्रमाण-पत्र देने के विषय पर बंबई में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में विदेशी फिल्मों का ही मसला छाया रहा. इसमें मानव संसाधनमंत्री नरसिंह राव सहित चार मंत्री उपस्थित थे. सम्मेलन इस नतीजे पर पहुंचा कि ये निम्न कोटि की फिल्में हैं और इनके आयात में सरकारी नियमों का उल्लंघन किया गया है.

दो सप्ताह बाद सरकार ने नई नीति की घोषणा की. इसके अनुसार अब सिर्फ उन्हीं विदेशी फिल्मों को आयात योग्य माना जाएगा जो पुरस्कृत हुई हों, बड़े अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में शामिल की गई हों, या प्रतिष्ठित विदेशी फिल्मी पत्रिकाओं में जिनकी अच्छी समीक्षाएं छपी हों. इसके बाद इन फिल्मों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा नियुक्त आयातित फिल्म चुनाव समिति से मंजूरी प्राप्त करनी होगी. इस समिति के अध्यक्ष मशहूर फिल्म निर्माता कांतिलाल राठौड़ हैं तथा इसके सदस्यों में बासु चटर्जी और गोविंद निहालानी जैसी फिल्मी हस्तियां हैं. इस समिति से मंजूरी मिल जाने के बाद भी उस फिल्म को सेंसर बोर्ड के सामने से गुजरना पड़ेगा. फिल्म समारोहों में सम्मिलित या प्रशंसनीय समीक्षा वाली फिल्मों के मामले में मार्ग-नियंत्रण फीस भी कम करके 10,000 डॉलर (1.3 लाख रुपए) कर दी गई है. पुरस्कृत फिल्मों को 8,000 डॉलर (1.05 लाख रुपए) की फीस पर ही अब आयात किया जा सकेगा.

इस नए कानून ने फिल्म विकास निगम के पर कतर दिए हैं. फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष मालती तांबे वैद्य को नई नीति की खबर अखबारों से मिली. उन्होंने कहा, "कोई टिप्पणी करने से पहले मैं इसका बारीकी से अध्ययन करना चाहूंगी."

नए कानून से आप्रवासी भारतीयों की पैसा उगलने वाली मशीन का मुंह बंद हो गया है. त्रिवेंद्रम में फिल्मोत्सव के अवसर पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय फिल्म बाजार में कुछ प्रमुख आप्रवासी फिल्म वितरकों ने इस नई नीति की घोषणा की खबर सुनते ही अपने स्टाल बंद कर दिए. लंदन स्थित आप्रवासी वाइ.एम. इलियास की इंडो-ओवरसीज फिल्म्स ने फिल्मोत्सव के बाजार स्थल— राज्य गेस्ट हाउस की दीवारों पर अपनी आने वाली मारधाड़ से भरपूर फिल्मों के पोस्टर चिपका रखे थे. पर वे नई नीति की घोषणा सुनते ही ये पोस्टर पीछे छोड़कर चलते बने.

नई नीति के अनुसार फिल्म विकास निगम के अलावा आयात करने वाली बाकी एजेंसियां भारत में वितरित की जाने वाली हरेक फिल्म के 15 प्रिंट तक मंगा सकेंगी. इस प्रावधान का मकसद दूसरे किस्म की धांधली यानी फिल्मों में बाहरी रीलें जोड़कर उसे उत्तेजक बनाने को रोकना है. सेंसर बोर्ड ने ऐसी 17 आयातित फिल्में पकड़ी हैं जिनमें कुछ उत्तेजक दृश्य अलग से जोड़े गए थे. सेंसर बोर्ड का दावा है कि उन्हें ये दृश्य कभी नहीं दिखाए गए.

वितरित की जाने वाली फिल्मों के प्रिंटों की संख्या पर रोक लगाने से स्थानीय फिल्म वितरक भी इन्हें ज्यादा अरसे तक प्रदर्शित कर सकेंगे. लेकिन दूसरे फिल्मी क्षेत्रों से नई नीति की कड़ी आलोचना के संकेत भी मिलने लगे हैं. आप्रवासी इलियास कहते हैं, "भारत में फिल्मों के अपने प्रिंट बनाने से रोकने की नई नीति हमारे लिए और मुश्किल पैदा कर देगी. क्योंकि यहां प्रिंट बनाने में हमारे सिर्फ 25,000 रुपए खर्च होते हैं लेकिन बाहर इसी के हमें 2000 डॉलर (करीब 26,000 रुपए) देने पड़ेंगे; इसके अलावा 30,000 रुपए प्रति प्रिंट की दर से सीमा शुल्क ऊपर से भरना होगा."

अश्लील फिल्मों का बाजार मंदा

देर से ही सही, सरकार की नींद टूटी और उसने विदेशी फिल्मों के आयात के नए नियम बनाने का फैसला किया

लेकिन अभी तो देखना है कि दरअसल होता क्या है. हालांकि व्यावसायिक दृष्टि से देखा जाए तो जैकी चान जैसों की या नंगधड़ंग औरतों वाली यह फिर इसी तरह की दूसरी अश्लील फिल्में गंभीर कला फिल्मों पर भारी ही पड़ती हैं.

यह ठीक है कि अब इस नई नीति से आप्रवासी फिल्म आयातकों को मात झेलनी पड़ेगी पर यह भी हो सकता है कि इसके कारण गेहूं के साथ घुन भी पिस जाए.

—श्रीधर पिल्लै

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

टी. राजन पोट्टवाल

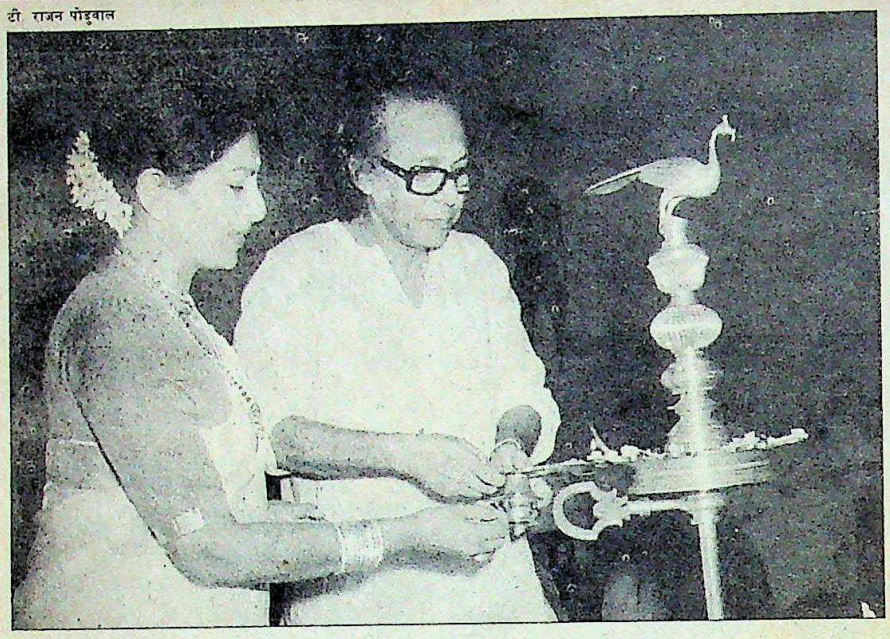

मृणाल सेन द्वारा उत्सव का उद्घाटन

फिल्मोत्सव

विवाद ही छाए रहे

पर फिल्मोत्सव '88 की उपलब्धियां भी कम नहीं रहीं

संगीतज्ञ, सजे हुए हाथी, केरल की साड़ी 'मंडम नरिथम' पहने और हाथ में फूलों से भरी थालियां लिए खड़ी लड़कियां— यह दृश्य था त्रिवेंद्रम में फिल्मोत्सव '88 की शुरुआत का. और जगह थी त्रावणकोर के पुराने राजमहल में स्थित 6000 दर्शकों की क्षमता वाली खुली रंगशाला— 'निसागंधी'.

पर परंपरा और रमणीयता के इस आभा-मंडल में जल्दी ही विवाद ने जगह बना ली. मुख्य अतिथि सत्यजित राय बीमारी के कारण आ नहीं सके. राज्य सरकार ने उनकी जगह मृणाल सेन को बुलाने के लिए फिल्मोत्सव निदेशालय पर दबाव डाला. पर निदेशालय राजीव गांधी को बुलाने का इच्छुक था.

इसके बाद विषाद का मुद्दा बनी उद्घाटन के समय दिखाई जाने वाली ब्रिटेन की फिल्म 'व्हाइट मिसचीफ.' यह फिल्म व्यभिचार पर थी और इसमें केन्या में ब्रिटिश राज्य के पतन का चित्रण था. मुख्यमंत्री ई.के. नयनार ने कहा, "यह फिल्म व्यभिचारिता से भरपूर है. इसमें सेक्स-ही-सेक्स दिखाया गया है. निश्चित ही यह फिल्म उद्घाटन समारोह पर दिखाए जाने के काबिल नहीं थी." पर फिल्मोत्सव की निदेशिका उर्मिला गुप्ता का कहना था कि 'वेरायटी' और 'साइट ऐंड साऊंड' जैसी पत्रिकाओं में छपी प्रशंसात्मक समीक्षाओं के आधार पर ही इस फिल्म का चयन किया गया था.

मृणाल सेन भी उनकी दलील से सहमत नहीं थे. उन्होंने बाकायदा बयान देकर इस फिल्म के चयन की निंदा की. पर फिल्मोत्सव निदेशालय ने उनका बयान जारी करने से इनकार कर दिया. आखिरकार यह [illegible] स्थानीय मेजबान केरल राज्य फिल्म [illegible] निगम (केराफिविकानि) के माध्यम से [illegible] रित किया गया. निगम को हिसाब [illegible] करना था क्योंकि उसे समारोह में जबरद[illegible] पीछे धकेल दिया गया था. निगम ने उद्घ[illegible] समारोह के निमंत्रण भेजने के लिए अ[illegible] सेवाएं देने की पेशकश की थी, पर फि[illegible] त्सव निदेशालय ने विनम्रतापूर्वक उ[illegible] अनुरोध ठुकरा दिया.

पर निदेशालय की किरकिरी तो तब जब उसने त्रावणकोर के पूर्व राजकुमार 'श्री व श्रीमती' के संबोधन से निमंत्रण भेज दिया. जबकि त्रिवेंद्रम में सभी जान[illegible] कि त्रावणकोर के नरेश ब्रह्मचारी हैं. [illegible] फिल्मोत्सव की संयुक्त निदेशिका [illegible]

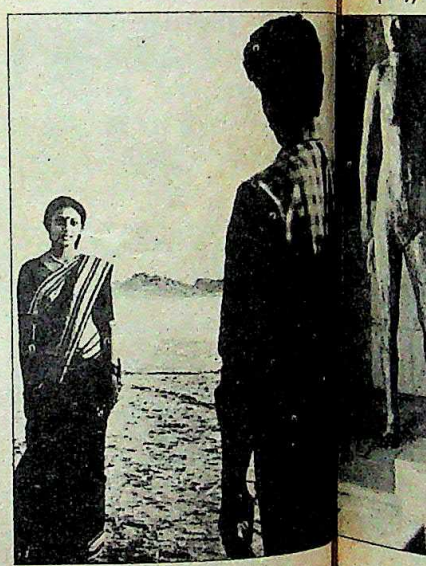

'अनंतरम' (दाएं) और 'पुरुषार्थम' के दृश्यः उत्कृष्ट प्रविष्टियां

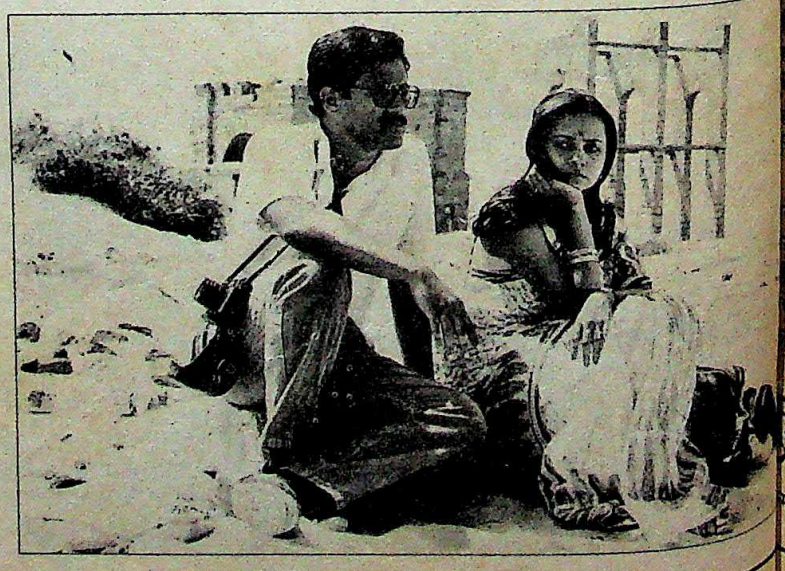

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सहाय को माफी मांगनी पड़ी.

फिर भोपाल गैस हादसे पर तपन बोस द्वारा निर्मित डाक्यूमेंट्री ऐन वक्त पर गायब हो गई. यह डाक्यूमेंट्री दिखाने की तैयारी हो गई थी, दर्शक हॉल में आकर बैठ भी चुके थे, तभी प्रोजेक्शनिस्ट ने पाया कि डाक्यूमेंट्री का तो प्रिंट ही नहीं है. मुमकिन है यह करतूत आयोजन करने वालों की राजनीति का नतीजा रही हो. हालांकि बाद में बोस की यह डाक्यूमेंट्री दिखा दी गई पर जो कुछ हुआ उससे फिल्मोत्सव निदेशालय की छवि में कोई चार चांद नहीं लग गए.

फिल्मोत्सव में हालीवुड की फिल्मों का आना फिर शुरू हुआ. पिछले वर्ष अमेरिकी चलचित्र संघ ने इसका बहिष्कार किया था.

विवादास्पद फिल्म 'व्हाइट मिसचीफ' (दाएं) और 'रेपेंटेंस' के दृश्य

...शी फिल्मों में अमेरिका की सबसे ...क—12 फिल्में थीं. जान-हस्टन की 'द ...' पर आलोचकों ने सबसे ज्यादा लिखा. ...रिका की कुछ अन्य अच्छी फिल्में थीं— ...एलेन की 'हाना ऐंड हर सिस्टर्स' और ...अन डे पाल्मा की 'द अनटचेबल्ज'.

...बदकिस्मती से इस साल दिखाई गई 120 ...शी फिल्मों में पड़ोसी देशों पाकिस्तान, ...लादेश और श्रीलंका की एक भी फिल्म ...थी. उधर फोकस अनुभाग हालांकि मध्य ...या को समर्पित था, पर इसमें भी रूसी ...मों की भरमार रही.

...छ अनुभागों का कोई औचित्य नहीं था. ...व्यावसायिक फिल्में इस बार 10 ही ...थीं जबकि पिछले साल ऐसी 21 ...मों को चोर दरवाजे से घुसाया गया था. इनमें बाक्स-आफिस पर हिट होने वाली 'नगीना', 'मिस्टर इंडिया' और 'चेब्बु' (तमिल) शामिल हैं.

भारतीय फिल्म सोसायटी महासंघ द्वारा आयोजित डाक्यूमेंट्री '88 का कार्यक्रम तो इससे भी अधिक संतोषजनक रहा. जूडी डरविन की डाक्यूमेंट्री 'डार्क सर्कल' परमाणु युग से संबंधित विवादास्पद फिल्म है जिसमें प्रभावित लोगों के माध्यम से बात कही गई है. सेफान जार्ल की 'द थरेट' में चेरनोबिल परमाणु हादसे से स्वीडन और नार्वे में हुए नुकसान की दास्तां है. 'माया, आई एम क्राइंग' और 'विटनेस टु एपारथेड' दक्षिण अफ्रीका में बच्चों को दी जा रही यातनाओं के विरोध में फिल्माई गई है. 'विन्नी ऐंड नेल्सन मंडेला' अश्वेत नेता नेल्सन मंडेला के जीवन पर आधारित वृत्तचित्र है. बोस की 'भोपाल, बिआंड जिनोसाइड' को भी प्रशंसा मिली.

सबसे अधिक निराशा तो इंडियन पैनोरमा अनुभाग से झलकती थी. पहले तो फिल्मोत्सव निदेशालय ने उनकी संख्या 21 से घटाकर 18 कर दी, जिससे काफी असंतोष पैदा हुआ. फिर इसमें एक भी तमिल या तेलुगु फिल्म को जगह नहीं दी गई. इसके बजाय मलयालम की छह और हिंदी की पांच फिल्में दिखाई गईं. इस पर तमिल और तेलुगु सिनेमा ने फिल्मोत्सव का बहिष्कार किया.

इंडियन पैनोरमा के उद्घाटन के लिए गिरीश कसारवल्ली की बेहद प्रशंसित फिल्म तबर्ण कथा (तबर्ण की कहानी) चुनी गई. पर यह फिल्म चूंकि दूरदर्शन के राष्ट्रीय कार्यक्रम में दिखाई जा चुकी थी इसलिए स्थानीय लोगों ने इसमें कम दिलचस्पी ली. गोपालकृष्णन की 'अनंतरम' विदेशी प्रतिनिधियों में हिट रही.

एक अन्य मलयालम फिल्म 'पुरुषार्थम' एक नौजवान व अमीर विधवा भद्रा वासुदेव की कहानी है, जिसे अपने पति की बहुत याद सताती है. विधवा की 'भूमिका सुजाता मेहता ने निभाई है. भारतीय फिल्म प्रशिक्षण संस्थान से निकले निदेशक के.आर. मोहनन इसमें नायिका के अंतर्द्वंद्व को दर्शाने में सफल रहे हैं.

असमिया फिल्म 'हलोधिया चनया बौधन काल' (फसल खाते पीले पक्षी) का निर्देशन जाहनु बरुआ ने किया है. यह एक किसान के संघर्ष की कहानी है जो अपने मां-बाप द्वारा जमींदार के पास गिरवी रखी जमीन छुड़वाना चाहता है.

इस अनुभाग की अन्य फिल्में कोई विशेष प्रभाव नहीं छोड़ पाईं. जिन थिएटरों में वे दिखाई गईं, वे लगभग खाली पड़े रहे. फिल्म समीक्षक खालिद मोहम्मद कहते हैं, "इंडियन पैनोरमा में दिखाई गई फिल्मों से लगता है सईद मिर्जा, गोविंद निहलाणी और कुंदन शाह सरीखे फिल्म निर्माताओं को, जो कभी नए सिनेमा आंदोलन से जुड़े थे, अब दूरदर्शन ने अपनी छत्रछाया में ले लिया है."

लेकिन फिल्मोत्सव '88 तकनीकी स्तर पर सफल रहा. फिल्मोत्सव के दिग्गजों और प्रतिनिधियों के अनुसार केरल राज्य फिल्म विकास निगम की दो रंगशालाओं, श्री और केराली में फिल्म दिखाने की सबसे अच्छी सुविधाएं थीं. उनमें 74 फीसदी टिकट तो हाथोहाथ बिक गए. उर्मिला गुप्त कहती भी हैं, "पिछले वर्ष मेरे निर्देशन में दिल्ली में आयोजित पहले फिल्म समारोह की तुलना में त्रिवेंद्रम का फिल्मोत्सव कहीं अधिक संतोषजनक और सफल रहा है. पर काश कि दर्शक भी उनकी इस भावना से सहमत हों!

—श्रीधर पिल्लै

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सम्मेलन

बढ़ती आवभगत

भारत के प्रति विदेशी आकर्षित

ऐसा लगता है कि देश में सम्मेलनों की बाढ़ ही आ गई है. भारत ढेर सारे स्वदेशी-विदेशी प्रतिनिधियों की मेजबानी में जुट पड़ा है. सम्मेलनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरे 200 करोड़ रुपए का व्यवसाय ही पनप आया है. सम्मेलनों में भाग लेने के लिए विदेशी प्रतिनिधियों के हुजूम भारत की ओर उड़ानें भर रहे हैं. एक अनुमान के अनुसार पिछले वर्ष देश में लगभग 1500 सम्मेलन आयोजित किए गए.

लेकिन यहां सिर्फ अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का ही जिक्र हो रहा है. छह साल पहले भारत में सिर्फ 92 अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुए थे. पिछले साल ऐसे सम्मेलनों की संख्या 500 तक जा पहुंची थी.

पिछले साल भारत ने जिस चतुराई से ग्यारह देशों की प्रतिद्वंद्विता के बीच 1994 में बायो केमिस्ट्री की 16वीं अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस आयोजित करने का जिम्मा ले लिया, उससे भी यही सिद्ध होता है कि भारत अब अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के नक्शे पर महत्वपूर्ण स्थान बनाता जा रहा है. यह कांग्रेस अब तक भारत में हुए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में सबसे बड़ी होगी. इसमें 7,000 प्रतिनिधि भाग लेंगे.

प्रतिनिधियों की भारी संख्या से आपको भले ही कोई सरोकार न हो, पर्यटन विभाग को जरूर है. विदेशी प्रतिनिधियों की बदौलत ही पिछले साल पर्यटन विभाग की कुल आय—1,780 करोड़ का कम-से-कम 10 प्रतिशत प्राप्त हुआ था. लेकिन इन सम्मेलनों से और अधिक लाभ उठाया जा सकता है. इंटरनेशनल कांग्रेस ऐंड कन्वेंशन एसोसिएशन (आईसीसीए) के विपणन निदेशक सुरेन कालरा भी कहते हैं कि "एक अध्ययन के अनुसार पर्यटकों के मुकाबले ये प्रतिनिधि तीन गुना अधिक पैसा यहां खर्च करते हैं."

सरकार ने भी सम्मेलनों से जुड़े परोक्ष लाभ को पहचान लिया है. इस साल पर्यटन विभाग देश में सम्मेलनों की बढ़ोतरी के लिए एक 'राष्ट्रीय सम्मेलन ब्यूरो' बनाने जा रहा है. राज्य पर्यटन विकास संस्थाएं, ट्रैवल एजेंसियां, होटल तथा एअर लाइन इस ब्यूरो के सदस्य होंगे. उन्हीं के वित्तीय सहयोग से यह काम भी करेगा.

सम्मेलन आयोजनों में भारत की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता के कई कारण हैं. नवें एशियाई खेलों के दौरान होटलों और कांफ्रेंस केंद्रों की बढ़ी संख्या से तो इन आयोजनों को और अधिक प्रोत्साहन मिला है. दिल्ली में जहां 80 प्रतिशत अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं, (दूसरे प्रमुख शहर हैं— बंबई, बंगलूर तथा कलकत्ता) बड़े होटलों की संख्या तेजी से बढ़ी है. 1981 में दिल्ली में 37 होटल ही थे, पिछले साल इनकी संख्या 50 आंकी गई थी. इसी तरह 1981 में जहां 4000 कमरे किराए पर उपलब्ध थे, अब लगभग दुगनी संख्या में हो गए हैं.

लेकिन दिल्ली के ताज पैलेस होटल की सम्मेलन प्रबंधक इंद्राणी मुखर्जी भारत की लोकप्रियता का एक और कारण बताती हैं, "विदेशों में भारत की छवि सुधारने के प्रयास निश्चय ही रंग लाए हैं. विदेशियों की नजर में भारत अब एक गरीब देश नहीं, बल्कि एक सुविधा-संपन्न आधुनिक राष्ट्र है." इसके अलावा भारत पश्चिमी देशों के मुकाबले काफी सस्ता भी है. एक और कारण है—विभिन्न क्षेत्रों में आपसी विचार-विमर्श की बढ़ती चाह. इसके लिए कांफ्रेंस से बेहतर कोई और माध्यम नहीं

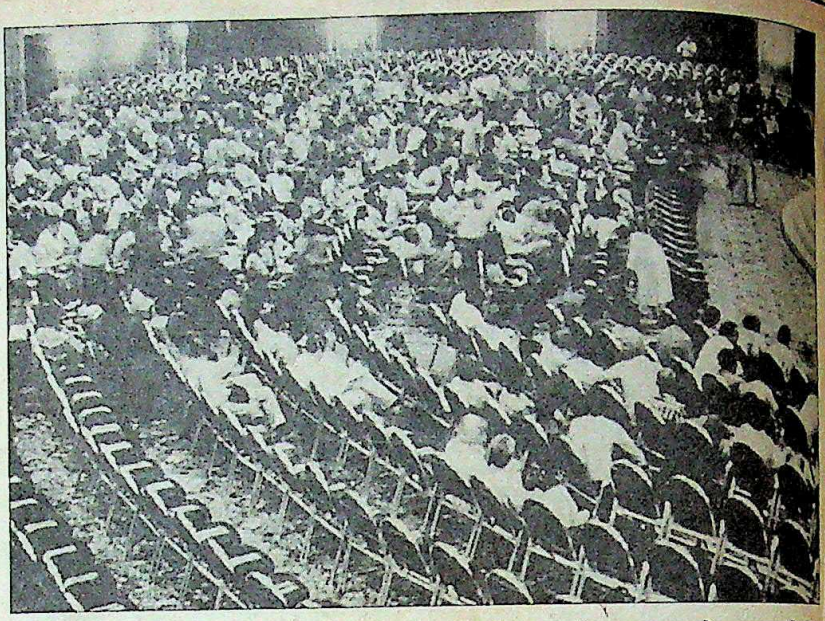

दिल्ली का सम्मेलन हाल: जोरदार कारोबार

पिछले साल पर्यटन से हुई 1780 करोड़ रुपए की कमाई में से कम-से-कम दस फीसदी तो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के आयोजन से हुई

ट्रैवल एजेंट, एअर लाइन और होटलों को तो ये सम्मेलन मोटे मुनाफे का धंधा नजर आते हैं. इनमें से कुछ तो कांफ्रेंस आयोजित कराने का जिम्मा भी लेते हैं. उन्होंने इसके लिए अपने यहां अलग कांफ्रेंस विभाग भी खोल रखे हैं.

सम्मेलनों की बढ़ती लोकप्रियता और लाभ की संभावनाओं को देखते हुए अब इन आयोजनों ने व्यावसायिक रूप ले लिया है. आइसीसीए का एक विभाग तो आयोजकों को सम्मेलन का विस्तृत ब्यौरा बनाने, बजट तैयार करने, सचिव सेवा प्रदान करने में सहायता देता है. दिल्ली का ताज पैलेस होटल और जम्मू-कश्मीर का पर्यटन विभाग तो अनुवादकों और सचिवों की सेवा सहित सम्मेलन केंद्र मुहैया कराता है.

लेकिन यह व्यवसाय भी समस्याओं से अछूता नहीं है. जैसा कि कालरा का कहना है, "मंत्रालयों से आयोजन की स्वीकृति में बहुत देर लग जाती है. अमेरिका में तो राष्ट्रपति सम्मेलनों को प्रोत्साहित करते हैं पर यहां अंतरराष्ट्रीय स्तर की गोष्ठियां कराने लायक पैसा भी नहीं होता."

लेकिन पर्यटन विभाग इन समस्याओं से अनभिज्ञ नहीं है. इस विभाग ने पहली बार भारत को एक 'उत्कृष्ट सम्मेलन स्थल' के रूप में प्रचारित करने 70 लाख रुपए का बजट तैयार किया है. भविष्य में शायद इस दिशा में और भी प्रयास किए जाएं. यदि ये प्रयास रंग लाए तो निश्चय ही भारत एक दिन विश्व की 'सम्मेलन स्थली' बन जाएगा.

—सुरजीत गांगुली

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

क्रिकेट

नए खून की लाली

मुद्दत के बाद मिली जीत से भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के सीने चौड़े

उन दुर्लभ, गौरवान्वित क्षणों में हर बात भुला दी गई थी—खिलाड़ियों के चयन को लेकर होने वाली तू-तू मैं-मैं, खिलाड़ियों और क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के कभी न खत्म होने वाले झगड़े और यहां तक कि अभी हाल में हुई शर्मनाक हार भी. भारत टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज को परास्त कर दे तो क्रिकेट के चाहने वालों के सीने चौड़े हो जाते हैं. पर मद्रास में हुई जीत खास तौर से सुकून भरी थी क्योंकि यह रिलायंस कप में हुई घनघोर निराशा और पाकिस्तान से टेस्ट शृंखला हारने के बाद मिली थी. कामचलाऊ कप्तान रवि शास्त्री उल्लसित होकर कहते हैं, "शृंखला का अंत अच्छा रहा. दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम को हराने के बाद कहीं भी जाएं, तो इतना आत्मविश्वास तो आ ही जाता है कि आधी लड़ाई यों ही जीत जाएं. ठीक कहा न मैंने?" उनके चेहरे पर जिस तरह का आनंद और उत्साह झलक रहा था वैसा किसी जमाने में भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को बार-बार देखने को मिल जाता था.

कप्तान की उल्लसित मुस्कान जरूर चिर-परिचित थी पर जिनकी बदौलत यह मुस्कान खिली, उनमें से ज्यादातर चेहरे नए थे. इनमें से एक थे धुन के पक्के, 19 वर्षीय वेल्लकला वेंकट रमन, जो प्रथम श्रेणी क्रिकेट में बगैर कोई शतक जमाए ही टीम में जगह पा गए थे पर जिन्होंने भारत की भरभराती दूसरी पारी को न सिर्फ बहादुरी से थामा बल्कि मैच जीतने लायक शानदार 83 रन भी बनाए. अब लगने लगा है कि वे मध्यक्रम की बल्लेबाजी में अरसे से चली आ रही बाएं हाथ के बल्लेबाज की कमी अब पूरी कर देंगे.

फिर अजय शर्मा भी थे जिन्होंने जानदार शॉट भले ही नहीं लगाए पर दृढ़ संकल्प का परिचय जरूर दिया और दोनों पारियों में महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई. और सबसे बड़ी बात तो यह कि भारत की इस नई नवेली-सी टीम में 19 बरस के नरेंद्र हिरवाणी थे, जो हाल के वर्षों में भारतीय क्रिकेट को मिले अनमोल रतन साबित हुए हैं.

जीवन के पहले टेस्ट मैच में कामयाब होने वालों की इस सूची में बल्लेबाज संजय मंजरेकर और ऑफ स्पिनर अरशद अयूब के भी नाम आ जुड़ते हैं. और इन्हीं से आधी टीम पूरी हो जाती है. इनमें से एक भी नाम ऐसा नहीं है जिससे क्रिकेट प्रेमी कुछ महीने पहले परिचित रहे हों. पिछले कुछ दशकों में भारतीय क्रिकेट का आकार इतने निर्णायक ढंग से कभी नहीं बदला था. यहां तक कि पिछले साल पाकिस्तान के साथ चली लंबी शृंखला में भी कोई नया चेहरा टीम में नहीं शामिल किया गया था.

अयूब (ऊपर) और (नीचे बाएं से) शर्मा और रमनः सफल शुरुआत

फोटो: प्रदीप भैद्यानी

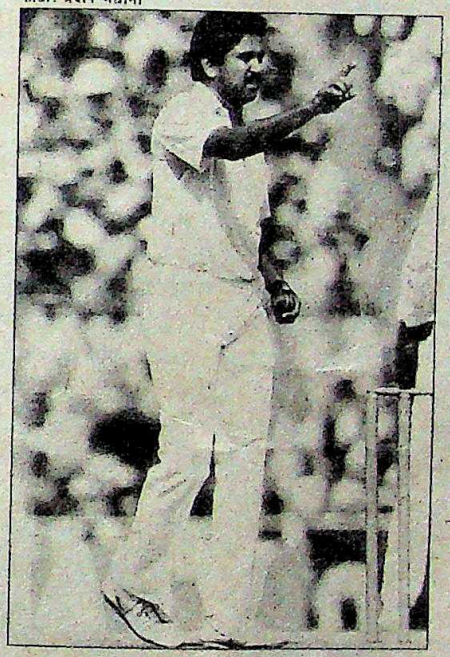

जगन्नाथ नेगी

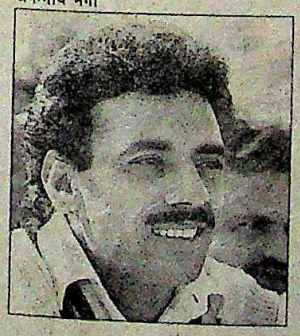

अतीत के परिप्रेक्ष्य में अधिकतर विशेषज्ञ अब तर्क देते हैं कि यह परिवर्तन तो होना ही था. "टीम में नए खून की जरूरत थी," एक चयनकर्ता कहते हैं. वे दुःखी हैं कि पाकिस्तान और श्रीलंका के विरुद्ध खेली टेस्ट शृंखलाओं में युवा खिलाड़ियों को तैयार करने का सुअवसर चयनकर्ताओं ने यों ही गवां दिया था. मद्रास टेस्ट की जीत का मुख्य श्रेय रमन, अजय शर्मा और हिरवाणी को देते हुए रवि शास्त्री स्वीकार करते हैं, "यह तो होना था. लंबे समय से लगभग वही पुरानी टीम खेल रही थी."

पर हिरवाणी की सफलता इतनी बड़ी थी कि रमन की प्रतिभा और शर्मा का दृढ़ संकल्प पीछे रह गया. टीम के एक वरिष्ठ सदस्य ने कहा, "यह कहना ठीक नहीं कि हिरवाणी को सभी विकेट पिच के कारण मिले. अगर पिच इतनी ही मददगार साबित हो रही थी तो दोनों तरफ के चार दूसरे स्पिनरों को कई-कई ओवर करने के बावजूद ऐसी कामयाबी क्यों नहीं मिली?"

विवियन रिचर्ड्स की शुरुआती आक्रामकता के बावजूद इंदौर के इस चश्माधारी लेग-स्पिनर ने विश्वासपूर्ण गेंदबाजी करके हरदम मीन-मेख निकालने वालों तक को प्रभावित कर दिया. उनकी गेंदों की ठुकाई होती तो वे गंभीरता से सोचते और जब विकेट मिलता, तो शांत रहते. शास्त्री कहते हैं, "मैं उसके साथ इससे पहले मैच में कभी नहीं खेला. सिर्फ नेट पर ही उसके साथ खेलने का मौका मुझे मिला और मैंने पाया कि वह पहले ही काफी परिपक्व है."

हिरवाणी एक ईंट भट्ठा मालिक के बेटे हैं. जब उनका वजन 70 किलो और कद 5 फुट और 6 इंच था, तो उन्हें मैच खेलने के नाकाबिल माना गया था. पर इससे निराश हुए बगैर वे अनवरत अभ्यास में लगे रहे और उन्होंने अपना वजन 16 किलो घटा लिया. रणजी मैचों के खिलाड़ी संजय जगदाले के संपर्क में आते ही वे उनके सबसे चहेते बन गए. गेंदबाजी के गुर उन्होंने जगदाले से ही सीखे हैं. पर हिरवाणी नम्रतापूर्वक कहते हैं, "मैंने बहुत मेहनत की. दिन में आठ-आठ घंटे नेट पर अभ्यास किया."

इसी परिश्रम का नतीजा है कि वे अब अनूठे लेग-स्पिनर बन गए हैं. वे अपने निशाने पर गेंद फेंकते हैं, गजब का धैर्य रखते हैं और खेल के मैदान में अपनी गेंदबाजी का सहजता से कमाल दिखाते हैं. दिग्गजों की राय है कि उनकी असली प्रतिभा का पता तो भविष्य में ही लगेगा पर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इसमें शक नहीं कि उनकी शैली मौलिक है. गावसकर कहते हैं, "भगवान का शुक्र है कि उसके सामने कोई आदर्श नहीं था."

फिर भी, जल्दी ही हिरवाणी का असली इम्तहान होगा. इस साल के आखिर में भारतीय टीम वेस्ट इंडीज जा रही है. विवियन रिचर्ड्स और उनके साथी चाहेंगे कि उनकी विकेट पर हिरवाणी की गुगली और फ्लिपर मद्रास की धूलभरी विकेट से कहीं ज्यादा साफ नजर आ जाए.

टेस्ट टीम में एकबारगी ही कई नौजवान खिलाड़ियों के आने का एक फायदा तो हुआ ही है कि ढीले पड़ रहे पुराने खिलाड़ियों में मुस्तैदी आ जाएगी. वरना वे शिकायत करते रहते थे कि लगातार अंतरराष्ट्रीय मैचों में खेल-खेलकर वे थक गए हैं. स्पर्धा होने के कारण अब टीम की दशा भी सुधरेगी. भी यह अजीब विरोधाभास है अंतरराष्ट्रीय मैचों के कारण ही खिलाड़ी मैदान में आ पाए हैं. इस घरेलू मैचों से भी जमे-जमाए खिलाड़ी और नए खिलाड़ियों को मौका मिल

नए खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा दे दिया है. इसलिए अब यह सवाल

नरेंद्र हिरवाणी

मेहनत का फल मीठा

किसी को उम्मीद नहीं थी कि चश्मा पहनने वाला यह ठिगना-सा लड़का इतनी जल्दी इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लेगा. पर मद्रास टेस्ट में दिग्गज टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ दोनों पारियों में 16 विकेट लेकर 19 बरस के लेग स्पिनर नरेंद्र हिरवाणी ने सभी को चमत्कृत कर दिया. वे न सिर्फ भारत की ओर से पहले टेस्ट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हो गए हैं बल्कि उन्होंने बॉब मैसी के विश्व रिकार्ड (16 विकेट 137 रन) को भी एक रन से सुधार दिया है. पूर्व टेस्ट खिलाड़ी कैप्टन मुश्ताक अली कहते हैं, "मुझे खुशी है कि करीब चार दशक बाद इंदौर से कोई आला दर्जे का क्रिकेट खिलाड़ी तो सामने आया. उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में इंदौर शहर को नया रुतबा दिला दिया है."

पर हिरवाणी मूलतः इंदौर के नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के हैं. इंदौर तो वे सिर्फ चार बरस पहले क्रिकेट सीखने और खेलने आए थे. पर अब इंदौर के बारे में वे कहते हैं, "मेरा यहां दिल लग गया है. मद्रास टेस्ट के बाद मैं सबसे पहले इंदौर पहुंचने और अपने 'गुरु' संजय जगदाले से मिलने को बेचैन था."

संजय जगदाले ने उन्हें सीसीआइ (क्रिकेट क्लब ऑफ इंदौर) में यों ही प्रवेश नहीं दे दिया था. हिरवाणी तब काफी मोटे थे. पूर्व शर्त पर हिरवाणी को सीसीआइ में प्रवेश मिला. संकल्प के धनी हिरवाणी ने 16 हफ्तों में 16 किलो वजन घटाने का अविश्वसनीय-सा काम कर दिखाया तो सीसीआइ के सूत्रधार और प्रशिक्षक संजय जगदाले दंग रह गए.

पर करीब एक दशक पहले खेलों के लिए अनजान शहर गोरखपुर के इस लड़के ने टेस्ट क्रिकेटर बनने की धुन पाल ली थी तो उसमें किसी को कोई संभावनाएं नजर नहीं आ रही थी. इस स्कूली लड़के के मंसूबों को बाल सुलभ सपने कहकर खारिज कर दिया जाता. विभाजन के बाद गोरखपुर में आकर ईंट भट्ठों का धंधा कर रहे दीपचंद हिरवाणी के पांच बेटों और दो बेटियों के सिंधी ठाकुर परिवार में व्यवसाय ही प्रमुख था.

गोरखपुर में हुमायूंपुर सिंधी कालोनी के निवासी और महाराणा प्रताप स्कूल के विद्यार्थी नरेंद्र हिरवाणी की क्रिकेट के प्रति लगन और समर्पण अद्वितीय था. गोरखपुर छोड़कर हिरवाणी लखनऊ स्पोर्ट्स कॉलेज

नरेंद्र हिरवाणी अपने प्रशिक्षक गुरु संजय जगदाले के साथ

चले गए. लखनऊ जाने का नतीजा यह हुआ कि उत्तर प्रदेश की पंद्रह वर्ष से कम उम्र के किशोरों की टीम में चुन लिए गए. पांच साल पहले वे इस आयु वर्ग के लिए संयोजित विजय मर्चेंट ट्रॉफी स्पर्धा खेलने इंदौर आए. पहली नजर में ही उन्हें क्रिकेट के शहर इंदौर से प्यार हो गया.

इंदौर के महाराजा शिवाजीराव हायर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययनरत हिरवा सीसीआइ में प्रशिक्षण के कड़े दौ गुजरे. 1984-85 के सत्र में उन्हें प्रदेश की रणजी टीम में चुन लिया रणजी टीम में चयन के पीछे टेस्ट क्रि अशोक मांकड का भी हाथ था. हिरवाणी ने 14 विकेट लिए थे. मैचों के अगले सत्र में हिरवाणी विकेट अपनी झोली में डाल लिए.

रणजी का 1986-87 का हिरवाणी नहीं खेले क्योंकि 19 कम उम्र की भारतीय टीम में उनका हो गया था और वे आस्ट्रेलिया के दौ थे. वहां तीन टेस्ट मैचों में उन्हें 23 मिले. लेकिन मद्रास तक का सफर तय में उन्हें फिर पूरा एक साल लग गया दौरान 1987 की शुरुआत में प्रवासी पाकिस्तान के खिलाफ फरीदा एक मैच खेला और लगातार तीन तक इमरान हिरवाणी की गेंदों कोई रन नहीं बना सके.

चंडीगढ़ में प्रवासी वेस्ट इंडी खिलाफ हिरवाणी भारतीय युवा की ओर से खेले और कुल जम विकेट उन्होंने लिए. अंतिम प सभी छह विकेट उनके नाम थे दरवाजे पर यह एक जोरदार थी और अंततः चयनकर्ताओं खोलना ही पड़ा. पूर्व राष्ट्रीय कर्ता मेजर एम.एम. जगदाले "हिरवाणी विनीत और महान क्रिकेटर बनने में ये गु लिए उपयोगी सिद्ध होंगे."

हिरवाणी की कीर्तिमान ने बेजार होते जा रहे पाव क्रिकेट को स्पंदित कर दिया है कृष्णन की विदाई के बाद वे भा में लेगब्रेक गुगली के अकेले पैरो

16 अक्तूबर 1968 को जन्मे हिरवाणी छोटे कद 5'4" के सिनेमा देखने का शौक है और अमिताभ बच्चन उनके प्रिय मद्रास में जब नरेंद्र हिरवाणी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ता है कि इनमें से कितने खिलाड़ी आक्रा- खिलाड़ी के रूप में उभरते हैं, कितने तार टीम में बने रहने के काबिल बन ते हैं और कितने टीम को विजयश्री का ाने लायक बन पाते हैं. एक दिग्गज ाड़ी कहते हैं कि लगभग एक दशक पूर्व देव की उपलब्धि के बाद से कोई मैच ने वाला खिलाड़ी नहीं उभर पाया. नई प्रतिभाओं की बाढ़ के बावजूद आज भी कपिल को ही नई गेंद फेंकनी पड़ती है. और दूसरे छोर से वैसी गेंदबाजी करने वाला आज भी कोई नहीं है. हालांकि अरुणलाल श्रीकांत के साथ सलामी बल्लेबाजी कर सकने वाले खिलाड़ी के रूप में उभर रहे हैं पर भरोसेमंद ओपनर वे अब भी नहीं बन पाए हैं. और फिर 31 बरस की उम्र में उनसे जवान होने की उम्मीद भी नहीं की जा सकती.

इस तरह भारतीय क्रिकेट के शिखर पर अभी भी जगह खाली है. यदि इसके लिए योग्य उम्मीदवार नहीं मिलता, तो इस साल के आखिर में जब भारतीय टीम का मुकाबला वेस्ट इंडीज से उनकी ही धरती पर होगा और वे अपनी हार का बदला लेना चाहेंगे, तब समस्या खडी हो सकती है. —शेखर गुप्ता

धर्मेंद्र शूटिंग के सिलसिले में वहां थे. में धर्मेंद्र हिरवाणी के होटल गए और मुबारकबाद पेश की. अपने प्रिय रे में रूबरू मिलकर हिरवाणी बहुत हुए. भोजन और कपड़ों को लेकर कोई खास उत्साह नहीं है. नेहरू डियम कैंटीन का बूंदी का रायता जरूर अच्छा लगता है. वे औसत विद्यार्थी रहे और अंग्रेजी उन्हें नहीं आती. हिरवाणी ते हैं, "अंग्रेजी मैं सीख लूंगा लेकिन हाल अच्छा क्रिकेट जरूरी है. आप ब खेलें और अच्छी अंग्रेजी बोलें तो से क्या फायदा?"

वे इंदौर के नेहरू स्टेडियम के एक कमरे ीकर रामू के साथ रहते हैं. कमरे की कानी से स्टेडियम प्रांगण में स्थापित के. नायडू की प्रतिमा साफ दिखती है. से उन्हें अनवरत अभ्यास की प्रेरणा मिली होगी. **शाहिद मिर्जा** से डेढ़ घंटे बातचीत में सवालों के जवाब उन्होंने ाते हुए दिए. बातचीत के अंश:

आपको विश्वास था कि आप टेस्ट में शामिल कर लिए जाएंगे?

हां, मुझे पूरा विश्वास था. जब मैं मैं मद्रास जाने के लिए हवाई न पर बैठा था, तभी मुझे इसका दिया गया था.

क्या आपको इतनी शानदार ता की आशा थी?

जब की अनिश्चितताओं वाले इस के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा . पर मुझे यकीन था कि मैं कम- आधा दर्जन विकेट तो जरूर ूंगा.

कप्तान और बाकी खिलाड़ियों के आपके संबंध कैसे रहे?

की प्रति सभी का व्यवहार अच्छा कपिल भाई, मोहिंदर भाई, रवि और टीम के सभी साथी मुझे भाई समझते थे. पहली विकट पर जब मोहिंदर भाई मुझे बधाई ए तो मैंने उनके पैर छू लिए थे.

आपने इंदौर ही क्यों चुना?

इंदौर में रहकर क्रिकेट सीखने का फैसला करने से पहले मैंने यहां के क्रिकेट के बारे में बहुत कुछ सुना था.

● आपने यहां क्या सीखा?

मेरा 'बॉलिंग एक्शन' ठीक नहीं था. सर संजय जगदाले ने मुझे इसे बदलने के लिए कहा. मैंने अपना क्षेत्ररक्षण (फील्डिंग) भी सुधारा.

● क्या पाकिस्तानी लेग स्पिनर अब्दुल कादिर ने भी आपको कुछ गुर सिखाए?

जब पाकिस्तान की टीम भारत आई थी, तब मैंने उसके खिलाफ फरीदाबाद में एक मैच खेला था. इसमें मैंने 31 ओवर फेंके, 64 रन दिए और सलीम युसुफ को आउट किया था. कादिर ने मुझे वहां खेलते देखा था और फिर इंदौर में भी देखा. वे बहुत खुश थे. उन्होंने मुझे बताया कि मेरी गेंद थोड़ी धीमी रहती है. उनकी सलाह थी कि तेजी लानी चाहिए क्योंकि तेज 'फ्लाइटेड' गेंद बल्लेबाजों को हिट लगाने के लिए ललचाती है और वे गलती करते हैं.

फिरकी गेंद का अद्भुत जादूगर हिरवाणी

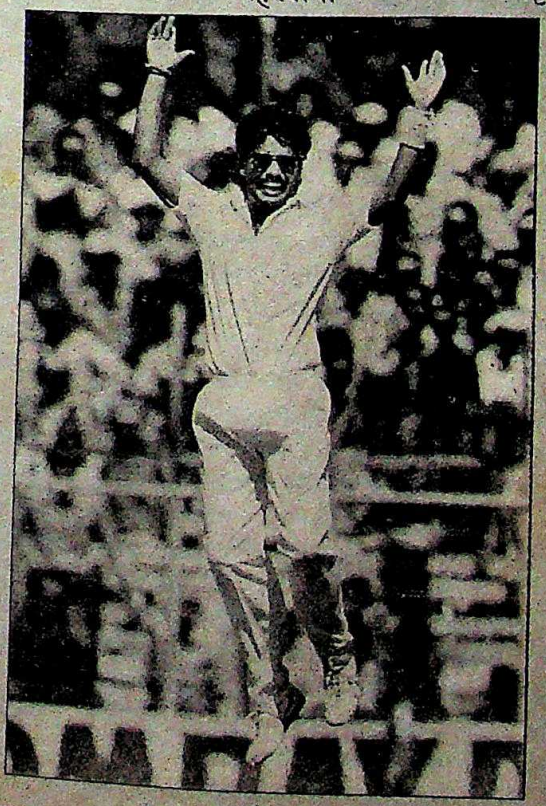

● अपनी सफलता का श्रेय किसे देंगे?

अपने गुरु सर संजय जगदाले और अपने माता-पिता को.

● 16 विकेटों के रिकार्ड के बाद भी आप खुशी से उछले क्यों नहीं?

दरअसल, विकेटों की मेरी भूख कभी खत्म नहीं होगी. मैं अधिक से अधिक विकेट लेना चाहता हूं. मैं अभी 19 साल का हूं. मुझे अभी बहुत खेलना है.

● आपमें इतना दृढ़ संकल्प और आत्म-विश्वास कैसे आया?

मैं हर गेंद फेंकने से पहले भगवान को याद करता हूं और प्रार्थना गुनगुनाता रहता हूं. यहां 'चैनल-9' वाली व्यवस्था होती तो आप मुझे प्रार्थना गुनगुनाते हुए भी टीवी पर सुन सकते थे.

● आपके आराध्य देवी-देवता.

हनुमानजी, शिवजी और गणेशजी.

● मद्रास टेस्ट में आपकी रणनीति क्या थी?

रणनीति मैं मैदान पर ही बनाता हूं. मैंने विवियन रिचर्ड्स को एक 'फ्लिपर' फेंकी क्योंकि मैं जानता था कि वे इस गेंद को पीछे हटकर खेलेंगे. मैं हर गेंद फेंकने से पहले सोचता हूं.

● आप तैयारी कैसे करते हैं, यानी प्रशिक्षण वगैरह?

जब मैचों का मौसम नहीं होता, तो सात-आठ घंटे कसरत करता हूं. और मौसम के दिनों में योगाभ्यास करता हूं. खूब दौड़ता हूं और नेट पर अभ्यास भी करता हूं.

● इंदौर कैसा लगता है?

मेरा यहां दिल लग गया है.

● आप अपनी बी.ए. की पढ़ाई पूरी करेंगे?

हां, मैं क्रिश्चियन कॉलेज, इंदौर में बी.ए. (प्रथम वर्ष) में पढ़ता हूं. मैं जरूर परीक्षा दूंगा.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पटना

तंबू ही तंबू

बस गई है 'धरना नगरी'

हर बड़े शहर में कुछ बस्तियां बनती हैं. मुहल्ले बसते हैं मगर बिहार की राजधानी पटना एक ऐसा शहर है जहां एक अजूबा नगर बस गया है. जहां हर किसी को धरना देने, नारे लगाने और या अनशन करने का पूरा अधिकार है. इस बस्ती को लोग 'धरना नगरी' के नाम से पुकारते हैं.

'धरना नगरी' बेली रोड पर रेलवे क्रासिंग और नए सचिवालय के पास पड़ती है. इसके दोनों ओर सरकारी बंगले हैं. यहां जो भी चाहे अपनी फरियाद लेकर आ जाए. अकेले आए या झुंड के साथ, चुपचाप अनशन करे या नारा लगाए. महीनों या वर्षों जमा रहे. थक जाए तो वापस चला जाए और फिर मन करे तो लौट आए.

इसके अलावा प्रदेश के कोने-कोने से आए विभिन्न संगठनों, संघों, महासंघों और राजनैतिक दलों के लोग अलग-अलग समस्याओं को लेकर जुलूस निकालते हैं और यहां आकर जोशीले भाषण करते हैं, सड़क जाम करते हैं और कभी-कभी पुलिस की लाठियां खाते हैं. इनमें सरकारी और अर्धसरकारी कर्मचारी, शिक्षक, बेरोजगार और पत्रकार सभी होते हैं.

राजेंद्र प्रसाद सिंह एक देहाती नौजवान और मुंगेर जिला क्रांतिकारी जनता पार्टी के नेता हैं. चारों ओर से खुली तिरपाल की पतली छत के नीचे एक पतले से कंबल में लिपटा यह युवक 21 जनवरी से आमरण अनशन पर है. सामने एक लाल कपड़े पर उनकी मांगें लिखी हैं. पूछने पर दबी आवाज में वे कहते हैं, "मुंगेर जिले के लक्ष्मीपुर ब्लॉक के अंतर्गत मसलयपुर गांव में एक सरकारी नलकूप लगवाने के लिए कई महीनों से अकेले लड़ रहा हूं. इसके पहले भी अनशन कर चुका हूं.

बगल के खेमे में 'बिहार राज्य विद्यार्थी संबद्धता प्राप्त संस्कृति महाविद्यालय संघ' के कुछ नेता और कार्यकर्ता 5 जनवरी से धरने और अनशन पर हैं. उनकी मांग है कि उनके कॉलेजों को वित्तीय सहायता दी जाए और विश्वविद्यालय से संबद्ध किया जाए.

पास के एक खेमे में 'बिहार बेरोजगार फार्मेसी स्नातक संघ' के कार्यकर्ता पिछले दो माह से धरने पर हैं. संघ के संयोजक आर.पी. शर्मा ने बताया कि बिहार में 250 फार्मेसी स्नातक सड़कों पर भटक रहे हैं.

सभी फोटो: इम्तियाज खान

यह एक तरह का मजार है, जहां लोग फरियाद लेकर आते हैं. कुछ की सुनी जाती है, कुछ की नहीं

राजेंद्र प्रसाद : कई महीनों से अकेले लड़ रहा हूं यह लड़ाई

दूसरी ओर 'बिहार प्रांतीय पीडब्ल्यूडी वर्कर्स यूनियन के लोग 28 दिसंबर से धरने पर हैं. एक साल पहले सरकार ने उनकी 10 सूत्री मांगों पर समझौता किया था पर सरकार अब उन्हें भूल गई है.

बिहार कृषि छात्र संघ ने अभी हाल में यहां अपना खेमा गाड़ा है. उनकी सात सूत्री मांगें हैं, जिसमें मुख्य है—सभी रिक्त स्थानों को भरने की.

'धरना नगरी' का इतिहास कोई पुराना नहीं है. इसकी नींव 1978 में जनता सरकार के समय पड़ी थी. हुआ यह था कि जेपी आंदोलन से निकले नौजवानों ने जनता सरकार से कुछ अधिक ही अपेक्षाएं कर ली थीं और वे कई मुद्दों पर हर दिन धरना और आंदोलन करने लगे थे. एक दिन आंदोलनकारियों ने विधानमंडल के परिसर में घुसकर विधायकों का रास्ता रोक लिया. और काफी हंगामा किया. तब से विधानमंडल और सचिवालय से दूर और ब्लॉक तक धरना, जुलूस पर पाबंदी लग गई. फिर क्या था, खेमे गड़ने लगे और धीरे-धीरे 'धरना नगरी' बस गई. यहां कैंप लगाना और धरना देना सबका मौलिक अधि हो गया. आसपास होटल भी खुल गए

यहां एक बात और हो रही है. जो यहां आता है सोचकर आता है कि उसे अवधि के लिए रहना है. इसलिए लायक झोंपड़ी बनाई जाती है. अगर की मांग पूरी हो गई या आश्वासन गया और वह जाने लगा तो अपनी दूसरों के हाथ बेच भी देता है.

लोगों ने बताया कि यहां अभी तो कुछ आसानी से मिल भी जाता है मगर विधानमंडल सत्र चालू होता है तो यह की भी जगह नहीं मिलती. 'धरना नगर फलने-फूलने से और वहां हंगामों से कभी बंगलों में रहने वालों की नींद हो जाती है. एक नेता ने इसे स्वीकार हुए कहा, "हम क्या करें? सरकार अनशन और आंदोलन के सिवाय और भाषा समझती ही नहीं". अगर सरकार यही हाल रहा तो जल्दी ही 'धरना पूरे शहर पर फैल जाएगी.

—हरवंश

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उत्तर प्रदेश

सचमुच सती या झूठमूठ

ललितपुर जिले में घटी घटना पर विरोधाभासी ब्यौरे

लगता है राजस्थान में रूपकंवर के सती होने की घटना से उभरे विवाद से उत्तर प्रदेश पुलिस को कुछ सीख मिली है. जब इसी तरह की एक घटना ललितपुर जिला मुख्यालय से सात किलोमीटर दूर मंडिया मिसर कस्बे (आबादी 200) में हुई तब पुलिस ने 'सती माता' की अर्चना के लिए इकट्ठे हजारों गांव वालों को तुरत तितर-बितर कर दिया. उन्होंने पति हरपाल सिंह यादव की चिता पर से शकुंतला की जली हुई लाश हटाने में भी बेहद तत्परता दिखाई.

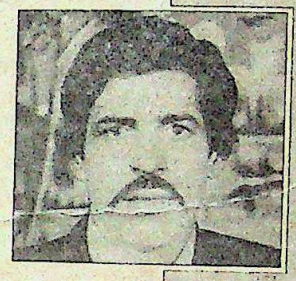

सती होने की घटना को नकारने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ पुलिस ने इसे हत्या का ही मामला बना दिया. हालांकि गांव वालों का दावा है कि शकुंतला ने आत्मदाह किया पर इसका कोई चश्मदीद गवाह नहीं होने के कारण उनकी बात पुलिस के गले नहीं उतरी.

कुछ भी हो, इस घटना का ब्यौरा काफी दिलचस्प है. 8 जनवरी को यह जानकर कि 35 वर्षीय हरपाल की एक दिन पहले किसी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है, शकुंतला अपने भाई राजेंद्र सिंह यादव के साथ मंडिया मिसर चली आई. हरपाल से अलग होने के बाद शकुंतला मध्य प्रदेश के बीना में रह रही थी.

शव परीक्षण के बाद 8 जनवरी को दिन में 2 बजे के आसपास हरपाल का अंतिम संस्कार कर दिया गया. दाह संस्कार की जगह पर शकुंतला करीब चार घंटे बाद पहुंची. हरपाल के भाई टीकाराम ने बताया, "वहां पहुंचकर वह दहाड़ें मार कर रोने लगी और चिता पर और लकड़ियां डालने लगी. हमने उसे जबरदस्ती वहां से हटाया." इसके बाद शकुंतला अपने ससुर चिमनलाल के घर गई. परिवार के सदस्यों के अनुसार वह लगातार दो रातों तक जागती रही. चिमनलाल ने कहा कि 10 जनवरी की सुबह 3 बजे तक वह जगी हुई थी. उस वक्त उन्हें झपकी आ गई थी. टीकाराम का कहना है कि शकुंतला ने शायद शाम होने से पहले ही पति की चिता दुबारा प्रज्वलित कर दी थी. 10 जनवरी की सुबह 6.30 बजे एक पड़ोसी ने दाह-स्थल पर शकुंतला की जली हुई लाश देखी. दिन में पौने दस बजे के करीब जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तब भी उसका शव सुलग रहा था.

पुलिस का मानना है कि शकुंतला की हत्या कहीं और करके बाद में उसकी लाश दाह-स्थल पर लाकर पटक दी गई ताकि हत्या का अपराध छिपाया जा सके. लेकिन पुलिस को चिमनलाल और टीकाराम के घरों को सील करने के बावजूद हत्या का कोई सबूत नहीं मिल पाया है. लगता है कि पुलिस ने शकुंतला के मरने से पहले उसके शरीर के ऊपरी हिस्से पर पड़े जलने के निशान नजरअंदाज कर दिए. लखनऊ के एक अपराध विज्ञान विशेषज्ञ बताते हैं कि जलने वाले के शरीर में पानी की भारी कमी होने के साथ ही मांस और कपड़े जलने के धुएं से उसका दम घुटने लगता है. इससे ऐसा लग सकता है कि दम घुटने से उसकी मौत हुई. अगर शकुंतला की हत्या की गई तो यह आश्चर्यजनक है कि उसके शरीर पर संघर्ष के कोई निशान नहीं मिले.

लेकिन पुलिस यह मानने के लिए तैयार नहीं कि अपने पति के दाहसंस्कार के 30 घंटे बाद कोई विधवा सती होने का फैसला भी कर सकती है. शकुंतला के ससुराल वालों का कहना है कि उसने तो पहले ही खुद को जला लिया होता लेकिन उनकी सतर्कता के कारण वह ऐसा नहीं कर सकी. हरपाल के बड़े भाई भवानी सिंह ने कहा, "दो दिनों के बाद हमने थोड़ी ढील दी. और उसने वही कर लिया जिसका हमें डर था."

पुलिस का यह भी कहना है कि 1974 से एक आपराधिक मामले में फंसे हरपाल ने अपनी दूसरी पत्नी शकुंतला को जून 1976 में शादी के दो महीने बाद छोड़ दिया था.

आर के गुप्त

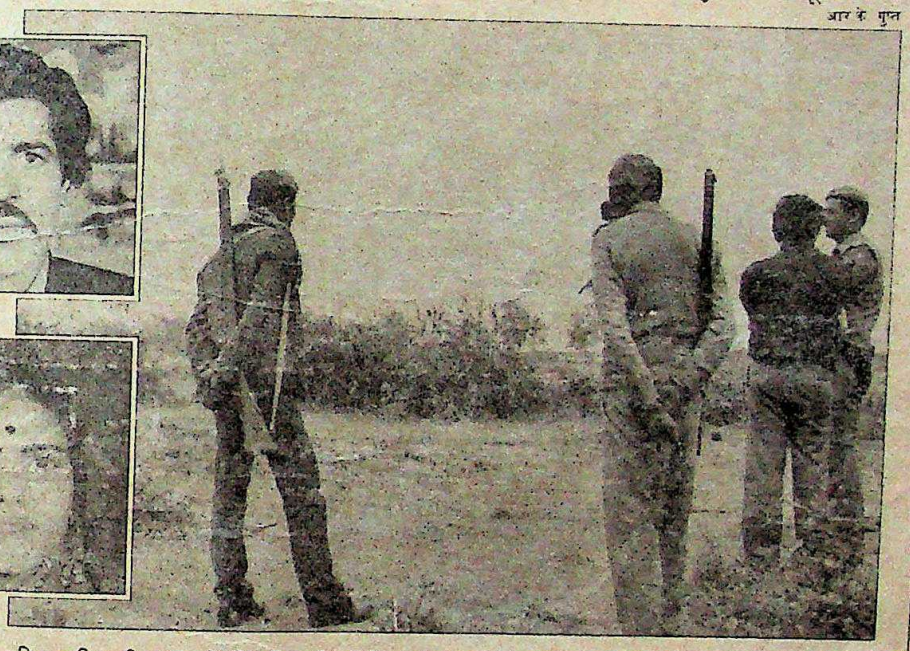

हरपाल तथा शकुंतला (इनसेट में) और दाहस्थलः लीपापोती

शकुंतला के मायके के लोग भी उसे 'सती' हुआ ही मानते हैं. उसकी बहन निर्मला ने कहा, "अगर हम कभी हरपाल के खिलाफ एक शब्द भी बोलते तो वह लड़ने लगती थी." मजे की बात यह है कि पुलिस ने उसके मायके वालों के बयान दर्ज नहीं किए हैं. इसी बीच राज्य सरकार ने पुलिस की जांच की तरह ही मामले की सीआइडी जांच का आदेश भी दे डाला है.

पुलिस अपने पुराने तरीके ही अपनाती दिखती है. अगस्त 1983 में बांदा जिले के पंगारा गांव में जब सती होने की एक घटना की खबर मिली थी तब भी हत्या का मामला दर्ज किया गया था. असल में, हत्या के मामले से निबटना सती के मामले से निबटने से कहीं ज्यादा आसान है.

—बिलीप अवस्थी, ललितपुर और बीना में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रमोद पुष्करणा

संगमरमर का प्रचलन

शाहजहां के पदचिन्हों पर

अब मध्यम वर्ग में भी संगमरमर की ललक बढ़ी

यदि आपसे कोई पूछ बैठे कि बादशाह शाहजहां और आज के शहरी मकान मालिक में क्या कोई साम्य है तो आप निश्चित ही हैरत में पड़ जाएंगे. लेकिन दोनों में एक साम्य है जरूर, वह है पत्नी से प्यार और संगमरमर से मोह. मुगल बादशाह ने अपने प्रेम को अमर बनाने के लिए संगमरमर का आलीशान मकबरा बनाया तो आज का बाबू रसोईघर के काउंटर पर संगमरमर जड़वाकर अपना प्रेम अभिव्यक्त करता है. सदियों बाद भी संगमरमर प्रेम की अभिव्यक्ति का एक मधुर माध्यम बना हुआ है.

राजाओं और राजमहलों के युग से संगमरमर ने एक लंबी यात्रा तय की है. यह कीमती पत्थर आज कई आलीशान बंगलों, पांचतारा होटलों और धनी-मानी व्यक्तियों की कोठियों की, जिनमें राजीव गांधी का फार्म हाउस भी शामिल है, शोभा बढ़ा रहा है और अब तो यह शाही पत्थर मध्यम वर्ग के घरों में भी तेजी से अपना स्थान बनाता जा रहा है. मकराना (राजस्थान) और मैसूर के व्यापारियों की भारी बिक्री संगमरमर और ग्रेनाइट उद्योग के तीव्र विकास का ही सूचक है. महानगरों में संगमरमर की तेजी से बढ़ती मांग का अधिकांश भाग इन्हीं दो स्थानों से पूरा किया जाता है.

संगमरमर की खपत में दिल्ली सबसे आगे है. इसका एक कारण तो यहां की 'कोठी संस्कृति' है और दूसरा यह कि दिल्ली से ही शेष उत्तरी भारत को संगमरमर भेजा जाता है. एक औसत दिल्ली निवासी के पास बंबई और कलकत्ता के निवासियों से अधिक रिहायशी स्थान है. यहां के सबसे बड़े संगमरमर विक्रेता श्रीचंद जैन का कहना है कि दक्षिण दिल्ली के बंगलों में औसतन 500 से 1500 वर्गफीट बढ़िया संगमरमर प्रयुक्त होता है.

संगमरमर की बढ़ती लोकप्रियता के दो प्रमुख कारण हैं—ऊंचा जीवन स्तर और उन्नत तकनीक. संगमरमर प्रोसेसिंग में उन्नत तकनीक से जहां तैयार संगमरमर के उत्पादन नई 'गैंग सॉ' मशीनों ने संगमरमर उद्योग में क्रांति ही ला दी है. इन मशीनों से आठ घंटे में ही 10 फीट ऊंचे खंड के इंच-इंच भर के टुकड़े किए जा सकते हैं. पहले इस [illegible] तकरीबन 15 दिन लग जाया करते थे।

इस नई मशीन के आने से संगमरमर [illegible] की कुल नई, अपेक्षाकृत हल्की किस्म 'मारबल' भी भवन निर्माण के लिए [illegible] हो गया है. उदयपुर के निकट पाय वाला यह संगमरमर जल्दी ही चटक था, इस कारण पुरानी मशीनों पर कटाई असंभव थी. लेकिन नई मशीनों से यह दिक्कत दूर हो गई। राजनगर संगमरमर बहुतायत से उप है ही, लोकप्रिय भी है. इस संगमर खानें राजस्थान में राजनगर और उद पास हैं. इन खानों में मकराना की जहां से ताजमहल के लिए संगमर

दिल्ली का संगमरमर बाजार बिक्री में बढ़ोतरी

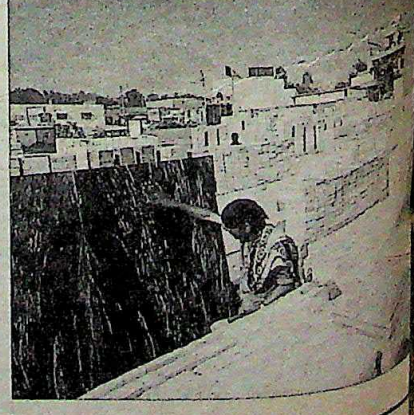

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रशांत पंजियार

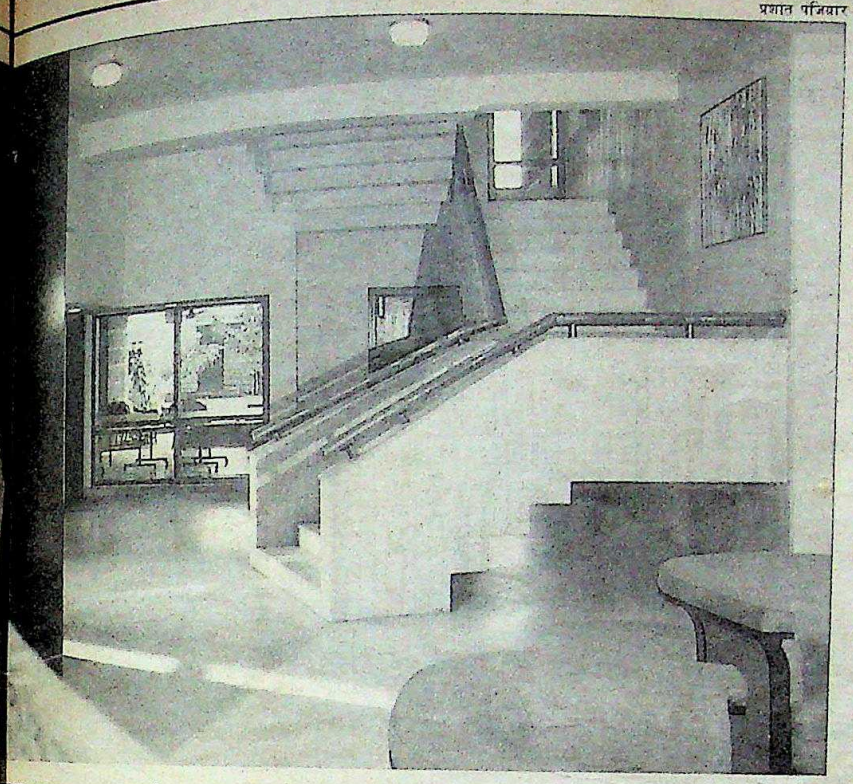

एक होटल का भीतरी हिस्सा (एकदम बाएं) और दिल्ली का एक घर

महानगरों के पांचतारा होटल भवन निर्माण और सज्जा के जैसे मानदंड बन गए हैं. और आज दिल्ली या बंबई में जो कुछ फैशनेबल माना जाता है, कल उसकी ही नकल देश के दूसरे शहरों में भी होने लगती है

पहले इस ...या गया था, कहीं बड़ी ...या करते ...त्रा में संगमरमर है. श्रीचंद ...से संगमर... की कुल बिक्री का 75 ...किस्म ...तिशत छोटे आकार की फर्श ...के लिए ...इलों से आता है. 'अखिल ...निकट पा... ...रतीय संगमरमर प्रोसेसिंग ...दी ही चट... ...' के सचिव और मकराना ...मशीनों पर ...मरमर के थोक विक्रेता ...किन नई ...क बंसल की कुल आमदनी ...र हो गई ... 40 प्रतिशत टाइलों और ...यत से उप... ...के निर्माण में इस्तेमाल होने ...इस संगम... ...संगमरमर की बिक्री से प्राप्त होता है. ...र और उ... संगमरमर की टाइलें मध्यम वर्ग को सहज ...राना की ...लब्ध कराने में स्वदेश निर्मित पत्थर ...लिए संगम... ...शने वाली मशीनें ज्यादा कारणीभूत हुई ...इनकी मदद से विक्रेता अब संगमरमर के ...तु पड़े टुकड़ों से काफी कम लागत पर ...ले तैयार कर सकते हैं. कम कीमत के ...ण ही ये टाइलें जन-साधारण तक पहुंच ...हैं. 'दिल्ली मारबल डीलर्स एसोसिएशन' ...अध्यक्ष रमेश बंसल का कहना है कि ...ले तो बड़े लोग ही घरों में संगमरमर ...वाया करते थे. अब साधारण व्यक्ति भी ...ने मकान का नवीकरण संगमरमर से ...वाना चाहता है."

...महानगरों के पांचतारा होटल भवन ...र्माण कला में मानो अनुकरणीय बन गए हैं. ...मरमर की लॉबी और स्तंभों से सज्जित ...ली का अशोक होटल जब खुला तो दिल्ली ...नाढ्य वर्ग में संगमरमर की सफेद टाइलों ...आर्डर देने की होड़ लग गई. वर्षों बाद जब मौर्य शेरेटन होटल की लॉबी में हरे रंग की टाइलें लगीं तो उन्हीं का फैशन चल पड़ा. अब राजौरी गार्डन के संगमरमर विक्रेता कम चौड़ाई वाली सफेद संगमरमर की टाइलों की मांग को पूरा करने में जुटे हैं क्योंकि दिल्ली के नए पांचतारा होटल 'मेरीडियन' में यही टाइलें लगी हैं. दिल्ली और बंबई में प्रचलित फैशन का अनुकरण दूसरे शहरों के लोग भी करने लगे हैं. मकराना के सबसे बड़े संगमरमर व्यापारी लाभचंद जैन का कहना है कि कुछ वर्ष पहले तक महाराष्ट्र में संगमरमर का प्रयोग घरों की नाम-पट्टिका बनवाने के लिए ही किया जाता था. लेकिन अब इन लोगों पर भी घर में संगमरमर लगवाने की सनक सवार हो गई है."

होटलों की ही बदौलत अब ग्रेनाइट उच्च वर्ग का पसंदीदा पत्थर बन गया है. जब संगमरमर पर मध्यवर्गीय पसंद का ठप्पा लग गया तो संभ्रांत वर्ग को इससे कोफ्त होने लगी. बंबई और दिल्ली के ओबेराय होटलों और दिल्ली के ही मेरीडियन होटल में लगे ग्रेनाइट की शीशे-सी चमक में उन्हें संगमरमर का विकल्प मिल गया. ग्रेनाइट के व्यापारी कन्हैयालाल का कहना है कि "दक्षिण दिल्ली के एक भवन निर्माता ने तुरंत ही अपने फार्म हाउस के फर्श पर काले और लाल रंग की ग्रेनाइट की टाइलें बिछवा दीं. दक्षिण दिल्ली के ही वसंत विहार के दुग्ध उत्पादन के एक प्लांट के मालिक ने तो अपने पूरे घर में ग्रेनाइट लगवाकर उसे एक दूतावास को भारी किराये पर उठा दिया.

दीपक बंसल मानते हैं कि घरों में संगमरमर लगवाना फैशन तो है ही, यह काफी किफायती भी है. जल्दी ही दिल्ली में संगमरमर का फर्श डलवाने का खर्च 14 रुपए प्रति वर्ग फुट के आसपास हो जाएगा, सीमेंट के फर्श पर संगमरमर की टाइलें लगवाने में भी तकरीबन इतना ही खर्च आता है. यदि खर्च समान न हो तो भी लोग संगमरमर का फर्श डलवाना ही अधिक पसंद करेंगे क्योंकि यह टाइलों के मुकाबले सुंदर और टिकाऊ तो है ही, इसे साफ करना भी बिलकुल आसान है. टाइलों में तो दरारें पड़ जाती हैं, जिनके भीतर धूल जम जाती है.

कपड़ों की तरह संगमरमर के फैशन में परिवर्तन आते रहते हैं. कुछ वर्ष पहले गहरे रंग की धारियों वाली सफेद टाइलें प्रचलन में थीं क्योंकि इन्हें जोड़कर आकर्षक नमूने तैयार किए जा सकते थे. लेकिन अब शुद्ध सफेद संगमरमर की मांग जोरों पर है. जगह की तंगी के कारण आर्किटेक्ट सफेद संगमरमर को ही प्राथमिकता देते हैं क्योंकि यह खुलेपन का भी आभास देता है.

संगमरमर अब कई रंग और किस्मों में उपलब्ध है. सफेद दानेदार मकराना संगमरमर जो ताजमहल बनाने में प्रयुक्त हुआ है, सफेद लेकिन हल्के हरे धब्बों वाला राजनगर संगमरमर, काली धारियों से युक्त सलेटी रंग का डूंगरी संगमरमर, उदयपुर का गुलाबी संगमरमर, जिसमें सलेटी धारियां पड़ी होती हैं, उदयपुर का ही हरा चित्तिदार संगमरमर जो बैंक काउंटरों और बड़े स्तंभों के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है. इसके अलावा जेब्रा जैसी सफेद-काली धारियों और चित्तियोंदार संगमरमर की मनमोहक किस्में भी अब बाजार में उपलब्ध हैं.

विश्व भर में ग्रेनाइट की खपत

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

के एक तिहाई भाग की आपूर्ति भारत से ही होती है. इसकी अधिकांश खानें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में स्थित हैं.

भारत में खनन किए गए कच्चे ग्रेनाइट का 90 फीसदी से भी अधिक भाग विदेशों को निर्यात किया जाता है. इनमें इटली का नाम सबसे ऊपर है, जहां ग्रेनाइट की शिलाओं को काटकर पॉलिश कर पुनः भारत भेजा जाता है. भारत के ग्रेनाइट उद्योग ने इस नीति का कड़ा विरोध किया है क्योंकि विदेश से पॉलिश करके आए ग्रेनाइट का मूल्य कच्चे ग्रेनाइट के मुकाबले दस गुना बढ़ जाता है. इंडियन ग्रेनाइट लिमिटेड, हैदराबाद के एल.बी. प्रसाद राव का कहना है कि यदि सरकार कच्चे ग्रेनाइट के निर्यात पर रोक लगा दे तो ग्रेनाइट का निर्यात 240 लाख डालर से बढ़कर 2400 लाख डालर हो सकता है. आंध्र प्रदेश सरकार ने इस सुझाव पर अमल किया है और लगभग 100 ग्रेनाइट प्रोसेसिंग इकाइयां राज्य में आरंभ की जा रही हैं. लेकिन कर्नाटक और तमिलनाडु में, जहां ग्रेनाइट का निर्यात राज्य द्वारा चलाए जा रहे निगमों के हाथ में है इस ओर ध्यान नहीं दिया है.

मोटे मुनाफे के बावजूद संगमरमर का व्यवसाय काफी कष्टसाध्य है. यदि आप थोक विक्रेता हैं तब तो और भी अधिक कष्टसाध्य क्योंकि आपको अधिकांश समय मकराना में बिताना पड़ेगा जो किसी सजा से कम नहीं है. समृद्धि के बावजूद अजमेर के निकट स्थित यह छोटा-सा कस्बा बेहद पिछड़ा हुआ है. यहां न तो अच्छी सड़कें हैं, न नालियां और न ही संफाई की उचित व्यवस्था. गर्मियों में धूल से लोगों का दम घुटने लगता है और बारिश के दिनों में सड़कें कीचड़ से लथपथ रहती हैं. लाभचंद जैन अपनी फैक्टरी के पास लगे कूड़े के ढेर की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि "कलकत्ता के अलावा किसी और जगह पर मैंने इतनी गंदगी नहीं देखी."

लेकिन यह गंदगी और पिछड़ापन बड़े उद्योगपतियों को यहां से दूर रखने की व्यावसायिक कूटनीति का ही एक अंग है. मकराना के छोटे खान मालिकों को डर है कि यदि मकराना भले आदमियों के रहने लायक बन गया तो मारवाड़ी सेठ यहां आ घुसेंगे. चूंकि फिलहाल इसके सुधार की कोई संभावना नजर नहीं आती, यहां के छोटे व्यवसायी, जिनका इस व्यवसाय के अधिकांश भाग पर नियंत्रण है, स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं. दिल्ली के युवा इंजीनियर अमरदीप सिंह ने मकराना में 'गैंग सॉ' मशीन लगाई है लेकिन वे ज्यादा-से-ज्यादा 15 दिन ही यहां रह पाते हैं. उसके बाद उनके भाई की कड़ी परीक्षा आरंभ हो जाती है जो बाकी के 15 दिन तक चलती है.

मकराना की अधिकांश खुली खदानों पर मुसलमानों का कब्जा रहा है. जैसे-जैसे परिवार की शाखाएं बढ़ती गईं, बंटवारों के कारण खदानों का आकार घटता गया. अब ज्यादातर खदानें दस-दस मीटर की पट्टी मात्र रह गई हैं. इसी वजह से खदानों के मालिकों की आर्थिक स्थिति वैसी ही है जैसी

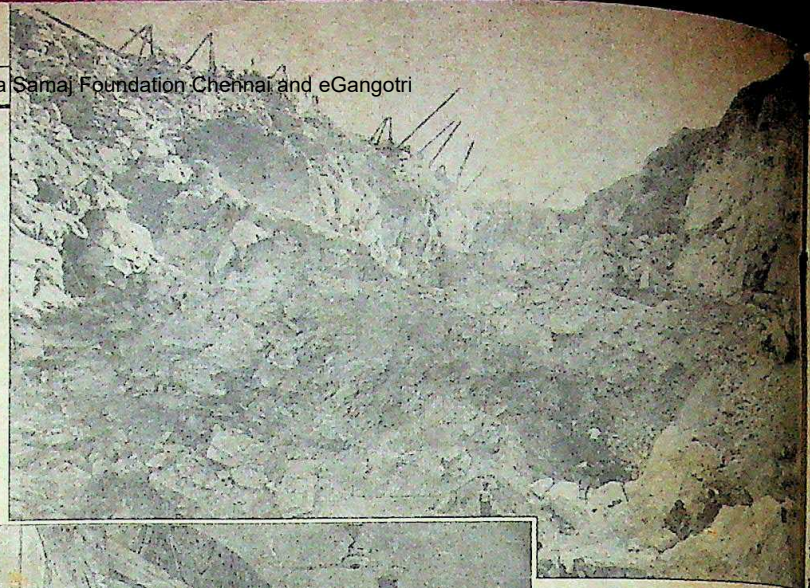

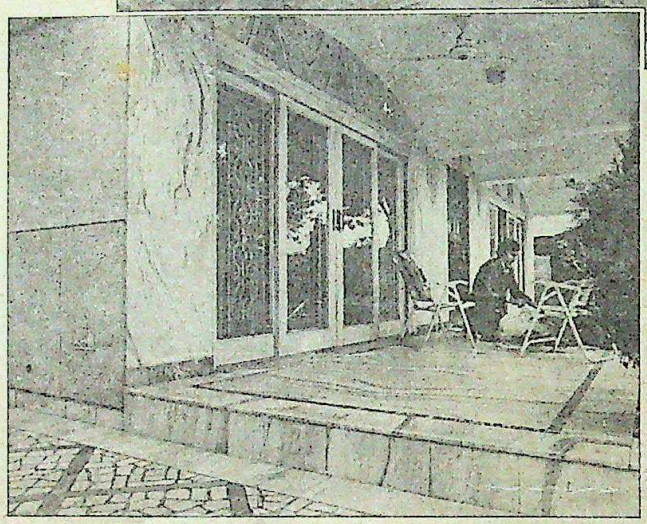

मकराना की खदान (ऊपर) और एक इमारत में संगमरमर का बेहिसाब इस्तेमाल

संगमरमर प्रोसेसिंग की उन्नत तकनीक और रहन-सहन के स्तर में सुधार के कारण संगमरमर और ग्रेनाइट की मांग बेहिसाब बढ़ी है

वर्षों पहले थी. यह व्यवसाय धीरे-धीरे बनियों और मारवाड़ियों के हाथ में आता गया जो कभी छोटे-मोटे ठेकेदारों के रूप में मकराना आए थे.

खानों की खुदाई आज भी पुराने ढर्रे से की जाती है. यह श्रमिकों के लिए कई घातक सिद्ध होती है. संगमरमर निकालने का तरीका आज भी वही है जो कभी ताजमहल बनने के समय रहा होगा. 300 से 400 मीटर गहरी खदानों में मजदूर रस्सी के सहारे नीचे जाते हैं और उसी प्रकार एक दूसरे का हाथ पकड़कर वापस आते हैं. यदि इन खदानों की नियमानुसार कटाई की जाती तो नीचे उतरना चढ़ना अधिक सरल होता. संगमरमर को काटने के लिए उसकी चट्टानों को डायमाइट से उड़ाया जाता है. इसमें से संगमरमर प्राप्त होता है उसका केवल 10 प्रतिशत इस्तेमाल करने के लायक होता है. इसी कारण भारतीय संगमरमर का मूल्य विश्व में सबसे अधिक है.

निश्चय ही संगमरमर आज न केवल वैभव और विलासिता का प्रतीक बन गया है बल्कि एक 'स्टेटस सिंबल' भी बन गया है. लाखों लोग इस मोहक, चिकने पत्थर को अपने घरों में लगवाने को लालायित हैं. अधिक नहीं तो अपने छोटे से गुसलखाने के फर्श पर संगमरमर लगवाकर ही वे आनंदातिरेक का अनुभव करते हैं. शाहजहां ने आगरे के किले से ताजमहल निहारकर किया होगा.

—रामेश्वर सिंह मकराना से
अनीता प्रताप द्वारा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मध्य प्रदेश

लहसुन के जरिये लखपती

मंदसौर जिले के किसानों ने ऐसी समृद्धि पहले नहीं देखी

अपनी गंध और तीखे स्वाद के कारण निकृष्ट माना जाने वाला लहसुन अब किसानों के लिए फायदे का सौदा साबित हो रहा है. केवल दो वर्षों में लहसुन की कीमतों में 900 प्रतिशत वृद्धि होने से मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के लहसुन उत्पादक अब रातोंरात लखपती बन गए हैं.

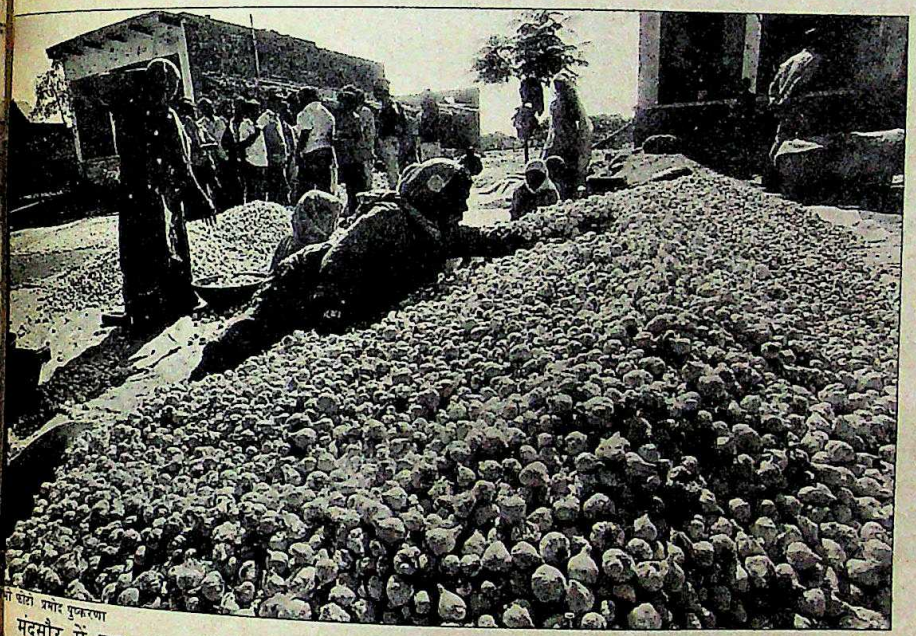

फोटो: प्रभात पुष्करणा

मंदसौर में यह खुशहाली जामनगर के किसानों की कीमत पर आई है. मूलत: लहसुन उत्पादक इस इलाके (जामनगर) में लगातार तीसरे साल भयावह अकाल पड़ने से लहसुन की कीमत 1984-85 के 200 रुपए क्विंटल से पिछले साल 1800 रुपए क्विंटल तक जा पहुंची. मंदसौर के किसानों ने मौके का फायदा उठाया और इस साल वे 300 करोड़ रुपए का लहसुन उगा रहे हैं. लहसुन ने इन किसानों की जिंदगी सचमुच ही जायकेदार बना दी है. नई-नई खुशहाली से यहां के गांवों की जीवन शैली भी बदलती जा रही है. लुनाखेड़ा गांव के एक छोटे लहसुन उत्पादक शांतिलाल भाव विभोर होकर बताते हैं, "मैंने जीवन में एक साथ इतना पैसा कभी नहीं देखा." पहले भी लहसुन की कीमतों में उतार-चढ़ाव आते रहे हैं लेकिन पिछले दिनों लहसुन के दाम जितनी तेजी से बढ़े हैं, उतने पहले कभी नहीं. 1983-84 में 550 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचने के बाद अगले वर्ष यह 200 रुपए प्रति क्विंटल पर उतर आया था. इसके बाद कीमतें तेजी से बढ़ीं. मंदसौर

स्थानीय मंडी में बिकने आया लहसुन: समृद्धि का वाहक

गुजरात में सूखे से फसल चौपट होने के कारण लहसुन के दाम आसमान छू रहे हैं. मंदसौर में इस साल 300 करोड़ रु. का लहसुन पैदा होगा

की मंडी में एक बार तो लहसुन की कीमतें कुछ समय के लिए 4,500 रुपए प्रति क्विंटल तक जा पहुंची थीं. इस साल लहसुन के धंधे में मोटा मुनाफा कमाने वाले मल्हारगढ़ मंडी के व्यापारी मुहम्मद इकबाल नागौरी मानते हैं कि "मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि लहसुन की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी."

व्यापारी ही नहीं, किसानों के लिए भी लहसुन उत्पादन फायदे का सौदा है. एक हेक्टेयर भूमि में लहसुन की बुवाई का खर्च केवल सात हजार रुपए आता है. और एक हेक्टेयर भूमि से 60-80 क्विंटल लहसुन निकल जाता है जिसकी कीमत लगभग एक लाख रुपए होती है. इसी कारण किसानों ने अब ज्यादा-से-ज्यादा इलाके में लहसुन उगाना शुरू कर दिया है.

पिछले तीन वर्षों में 7,400 हेक्टेयर भूमि में लहसुन उगाया जाता था. पिछले साल यह इलाका बढ़कर 14,000 हेक्टेयर हो गया और एक अनुमान के अनुसार इस मौसम में 28,000 हेक्टेयर भूमि में लहसुन बोया गया है, जिससे रबी में 1.68 लाख टन लहसुन प्राप्त होने की संभावना है.

देश के कुल अफीम उत्पादन का 60 प्रतिशत हिस्सा देने वाले इस क्षेत्र के किसानों के लिए लहसुन एक नया नशा बन चुका है. कई किसानों ने तो इस बार अफीम उगाने के लाइसेंसों का भी नवीकरण नहीं कराया है, क्योंकि अब उन्होंने लहसुन की बुवाई शुरू कर दी है. इस साल केवल 4,384 हेक्टेयर भूमि में अफीम उगाई गई और लहसुन 15 फीसदी क्षेत्र में. कराडिया गांव के प्रभुलाल, जिन्होंने अपनी 8 हेक्टेयर की जोत में से 6 हेक्टेयर में लहसुन बोया हुआ है, इसका स्पष्टीकरण यों देते हैं, "अफीम की फसल से प्रति हेक्टेयर 17,500 रुपए का ही मुनाफा होता है, जबकि लहसुन से एक लाख रुपए का."

लहसुन से होने वाले मुनाफे को किसानों ने कृषि के आधुनिकीकरण पंपिंग सेट, ट्यूबवेल, ट्रैक्टर वगैरह में लगा दिया है. नारायणगढ़ गांव में अपनी 15 हेक्टेयर जमीन में से एक तिहाई में लहसुन उगाने वाले जगदीशचंद्र ने मुनाफे की राशि का बड़ा भाग सिंचाई पर खर्च कर दिया है.

इस जिले में ट्रैक्टरों की बिक्री प्राय: दुगनी हो गई है. नीमच में ट्रैक्टरों की नामी कंपनी के एक डीलर रवि पोरवाल कहते हैं, "किसान हमारे पास थैलों में या तौलिए में रुपए लपेटे आते हैं तथा नकद रकम देकर ट्रैक्टर खरीद ले जाते हैं." नए ट्यूबवेल लगवाने की भी होड़ लग गई है क्योंकि माना जाने लगा है कि जितना ज्यादा पानी उपलब्ध होगा, आमदनी भी उतनी ही बढ़ जाएगी. दो रिग्स (कूप खनन संयंत्रों) के मालिक मोहन जिंदा कहते हैं, "एक ट्यूबवेल लगवाने पर 35,000 तथा 40,000

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रुपए के बीच खर्च आता है. लेकिन फिर भी किसान ट्यूबवेल लगवाने के लिए नकद रुपए लेकर आते हैं.'' दो साल पहले तक जिले में ट्यूबवेल लगवाने की एक भी दुकान नहीं थी. लेकिन अब 10 दुकानें धड़ल्ले से चल रही हैं.

कई किसान तो अब अपनी आमदनी दूसरे व्यवसायों में भी लगाने लगे हैं. जैसे नारायणगढ़ गांव के भरत सिंह अपने परिवार के 40 हेक्टेयर खेत में से 6 हेक्टेयर में लहसुन की खेती करते हैं. उन्होंने एक पुराने ट्रैक्टर के अलावा दो नए ट्रैक्टर ही नहीं खरीद लिए बल्कि दो ब्लास्टिंग मशीनें भी खरीद ली हैं. इन मशीनों से वे इस क्षेत्र में कुंए खोदने का काम करते हैं.

इससे आई संपन्नता जिले में हर जगह दिख जाती है. मल्हारगढ़ तहसील के कनकट्टी गांव (आबादी: 3000) में अब 55 मोटरसाइकिलें, तीन जीपें और एक केबल टीवी हो गया है. ये सभी चीजें कुछ महीने पहले ही खरीदी गई हैं. कराडिया गांव तो और भी छोटा है. (आबादी: 500) लेकिन पिछले छह महीने के दौरान यहां भी चार नए ट्रैक्टर और 20 मोटरसाइकिलें खरीदी गई. अभी पिछले महीने ही इस गांव में एक डिश एंटेना लगवाया गया. नीमच में लोकप्रिय मोटरसाइकिलों के एक थोक व्यापारी नोसची जाल का कहना है कि एक साल में ही उनकी बिक्री दुगनी हो गई है. नई खरीदी गई इन ट्रैक्टरों, ट्रॉलियों तथा मोटरसाइकिलों में से अधिकांश पर 'लहसुन कृपा' का नारा लिखा होता है.

जिले के ज्यादातर हिस्से में टीवी के संकेतों के ग्रहण की क्षमता नहीं है. इसलिए डिश एंटेना की यहां बड़ी मांग है. डिश एंटेना से उपग्रह संकेतों के ग्रहण में सहायता मिलती है. ऐसे 150 एंटेना लग चुके हैं. अधिकांश गांवों में स्थानीय केबल टीवी भी लगा लिए गए हैं जिन पर प्रायः हर रात हिंदी फिल्में दिखाई जाती हैं. जीरन (आबादी 7000) जैसे अनेक बड़े गांवों में तो बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए दो-दो केबल टीवी नेटवर्क लगा लिए गए हैं. इन गांवों में कुछ किसान तो दोनों केबल टीवी नेट-वर्क के ग्राहक हैं, इस तरह उन्हें

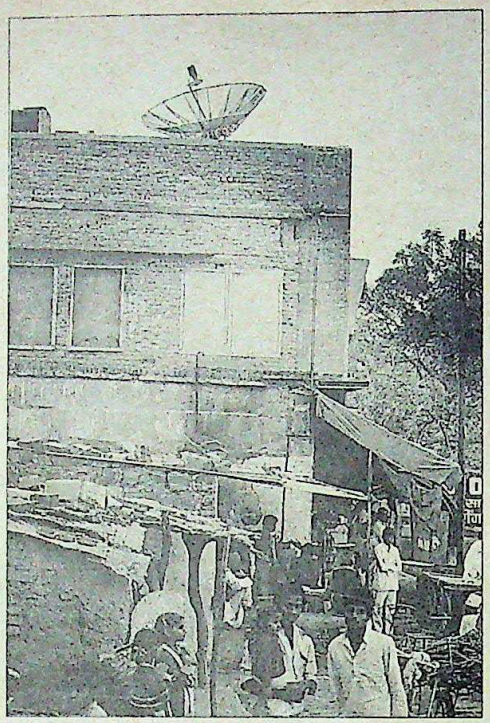

जीरन गांव में निजी डिश एंटेना

लहसुन से आई समृद्धि से जीवन शैली भी बदल रही है. किसान अपना मुनाफा उपभोक्ता सामग्रियों और खेती के औजारों पर खर्च कर रहे हैं

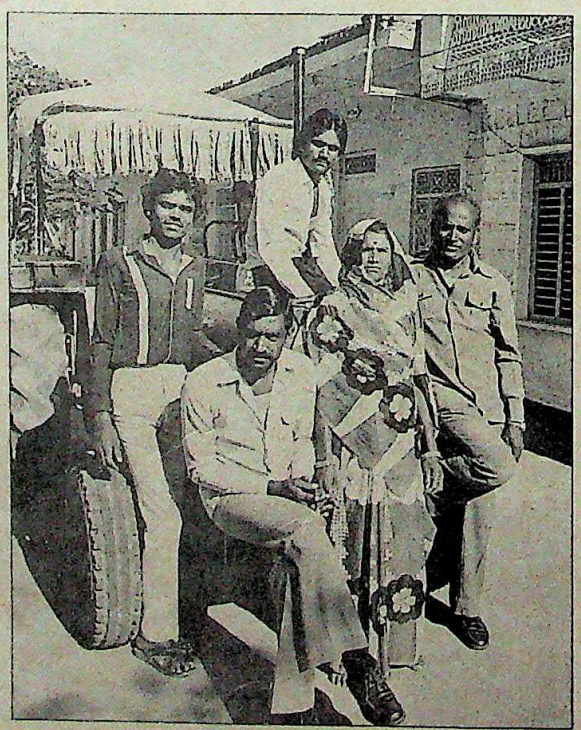

नए ट्रैक्टर पर किसान परिवार

अपनी पसंदीदा फिल्मों के चुनाव के ज्यादा अवसर मिल जाते हैं. वर्तमान आमतौर पर 100 टीवी सेटों को चलाने के लिए एक डिश एंटेना लगाया जाता है. नीमच में टेलिवीजन के एक थोक व्यवसायी दामोदार मुखाल के अनुसार पिछले तीन सालों में टीवी सेटों की मांग 40 प्रतिशत बढ़ गई है.

लेकिन लहसुन की ऊंची कीमतों के कारण कई दूसरी समस्याएं भी पैदा हो गई हैं. खेतों से लहसुन की चोरी आम हो गई है. पिछले पखवाड़े, गुडभेली गांव के तीन मकानों में डकैतों ने डाका डाला और लहसुन के सात बोरों के सिवाय और कुछ नहीं ले गए.

बड़ी रकम की लेनदेन से इस इलाके में बैंकों का कारोबार भी बढ़ गया है. लहसुन पैदा करने वाले अधिकांश किसानों ने अपने कर्ज चुका दिए हैं और को ब्याज़ देने से बचने के लिए वे नकद खरीदी ज्यादा करने लगे हैं. जीरन गांव में एक बैंक की जमा राशि पिछले साल 37 लाख रुपए से बढ़कर 57 लाख रुपए तक हो गई.

किसानों की इस समृद्धि का असर दूसरे क्षेत्रों में भी पड़ा है. जीरन इलाके में सिंचित जमीन की कीमत 20,000 रुपए प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 35,000 रुपए हो गई है व्यापारियों की समृद्धि काफी बढ़ गई है. मल्हारगढ़ के एक व्यापारी ने बताया कि पिछले साल उसने लहसुन से 3 लाख रुपए कमाए.

समृद्धि की लहर अब शहरों में भी पहुंच रही है. वहां कारोबार बढ़ गया है. मसलन नीमच मंडी कमेटी का राजस्व दो सालों में दुगना हो गया. 1984-85 में 12.7 लाख रुपए से बढ़कर पिछले साल 25.5 लाख रुपए पहुंच गया.

कुछ लोगों का मानना है कि समृद्धि का यह दौर हमेशा कायम नहीं रहेगा क्योंकि जामनगर इलाके में सूखा हमेशा नहीं रहेगा और लहसुन के दाम अपने पहले के स्तर पर आ जाएंगे. इस बात में कुछ सचाई भी है. लेकिन फिलहाल मंदसौर के किसान अपनी समृद्धि के लिए इस 'सफेद सोने' में अपना विश्वास कायम रखे हुए हैं.

—नरेंद्र कुमार

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जीवन के रंग अजीब...

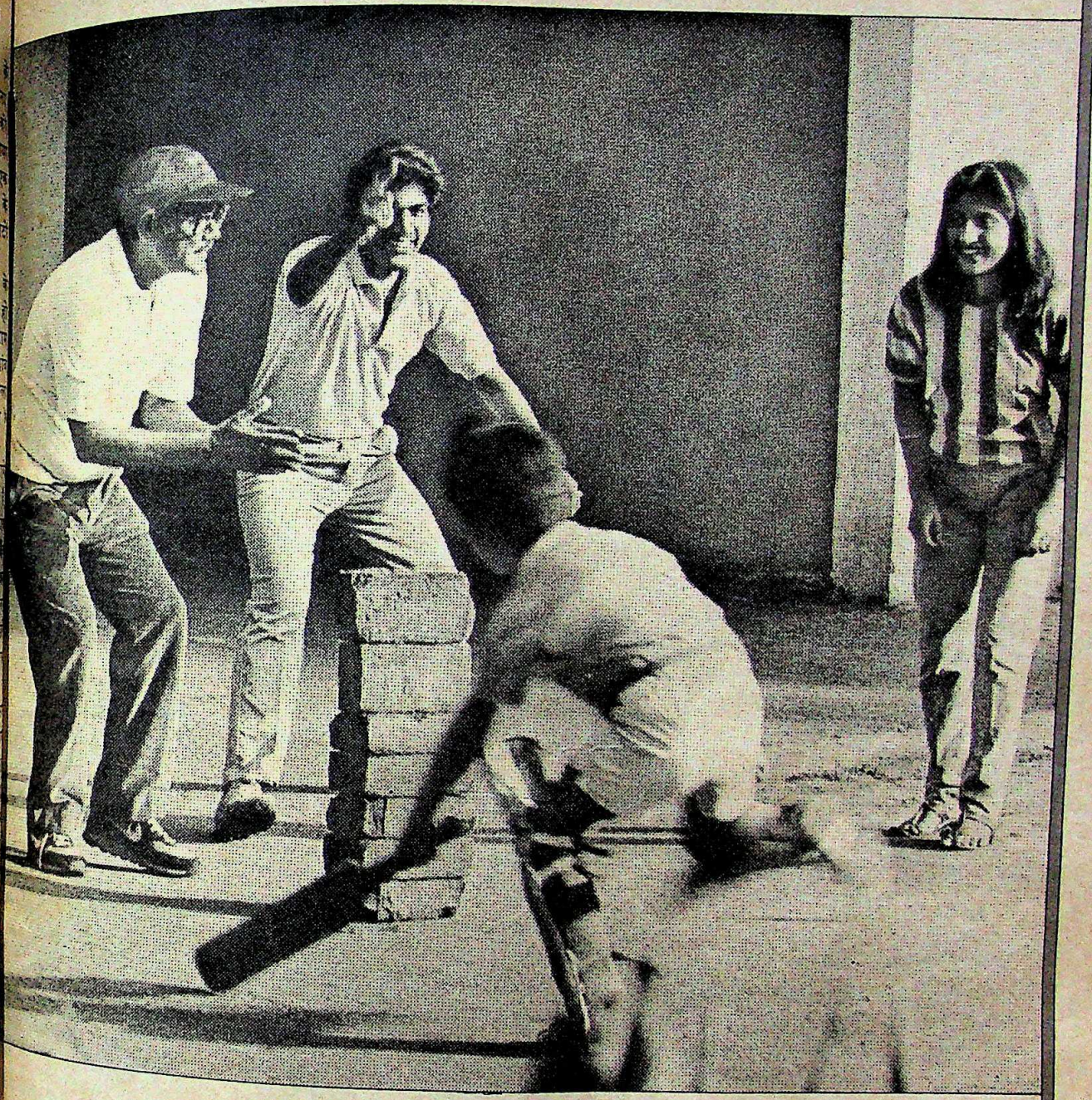

शुक्र है बोरोलीन करीब

खुशबूदार ऐन्टिसेप्टिक क्रीम

सूखी त्वचा और साधारण कटने-छिलने पर अनोखा असर

साठ साल पहले अव्वल, आज भी अव्वल

बोरोलीन प्रसाधन सामग्री नहीं

जी डी फार्मास्युटिकल्स
कलकत्ता ७०००५३

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

असम

चलते-फिरते कल्पना लोक

राज्य में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं ये चल-थिएटर

चलते-फिरते थिएटर असम में तेजी से लोकप्रिय होते जा रहे हैं. पिछले पखवाड़े इन थिएटरों द्वारा खेले गए नाटकों को— जिनमें पौराणिक कथाओं से लेकर राजनैतिक व्यंग्य तक शामिल थे— जिस चाव दर्शकों ने देखा, उससे तो यही सिद्ध हुआ कि ये चलते-फिरते थिएटर शीघ्र ही असम जन संस्कृति का अंग बन जाएंगे.

जात्रा के आयोजक अच्युत लाखर ने जब 1963 में पहला चल-थिएटर आरंभ किया तो उन्हें इस बात का तनिक भी एहसास नहीं था कि ये लोगों की कल्पनाओं को इस हद तक आलोड़ित कर देंगे. लाखर तथा ब्रजनाथ सरमा आदि कई व्यक्तियों ने पुरानी जात्राओं को एक नई शैली में अधिक ग्राह्य तथा जीवंत बनाकर मंच पर प्रस्तुत किया. आज असम में ऐसे 30 चलते-फिरते थिएटर हैं, इनमें से अधिकांश बारपेटा जिले के पाठशाला कस्बे (जनसंख्या: 30,000) में चल रहे हैं.

दो महीनों के कड़े पूर्वाभ्यास के बाद सितंबर के मध्य में ये ग्रुप राज्य के दूर-दराज इलाकों में अपनी सात माह लंबी भ्रमण गाथाओं का कार्यक्रम शुरू करते हैं. प्रत्येक ग्रुप में लगभग 100 कलाकार होते हैं. और ये कम से कम 50 स्थानों पर शो का आयोजन करते हैं. इन कार्यक्रमों के टिकटों की बिक्री भी धड़ल्ले से होती है.

सामयिक कथ्य की प्रभावशाली प्रस्तुति के लिए आधुनिक मंच तकनीक का सहारा लिया जाता है. दो दृश्य बदलने में समय नष्ट होने से बचाने के लिए तथा कई बार एक साथ दो-दो घटनाएं दिखाने के लिए दोहरे मंच तैयार किए जाते हैं. प्रकाश और ध्वनि व्यवस्था के कुशल संयोजन के कारण आवश्यकता अनुसार बादल, धुआं, आग और यहां तक की समुद्री लहरों के विशेष दृश्य बखूबी दिखाए जा सकते हैं.

इन नाटकों का एक और सुखद पहलू यह है कि चाहे व्यावसायिक दृष्टि से ही सही अश्लीलता को कोई स्थान नहीं दिया गया है. प्रतिभाशाली कलाकारों, निर्देशकों और लेखकों के इस आंदोलन से आ जुड़ने का एक प्रमुख कारण इनकी साफ-सुथरी छवि ही है. सुरेन महंत, निपोन गोस्वामी, बिजोय शंकर दास, बिजू फूकन, बिदया राव, रेणु देवी, प्रांजल सैकिया जैसे सुप्रसिद्ध फिल्म कलाकार भी वर्ष में से नौ महीने इन थिएटरों में ही काम करते हैं क्योंकि फिल्मों में तो 20 हजार से 60 हजार रुपए पारिश्रमिक मिलता है जबकि ये थिएटर अपेक्षाकृत अधिक पारिश्रमिक देते हैं.

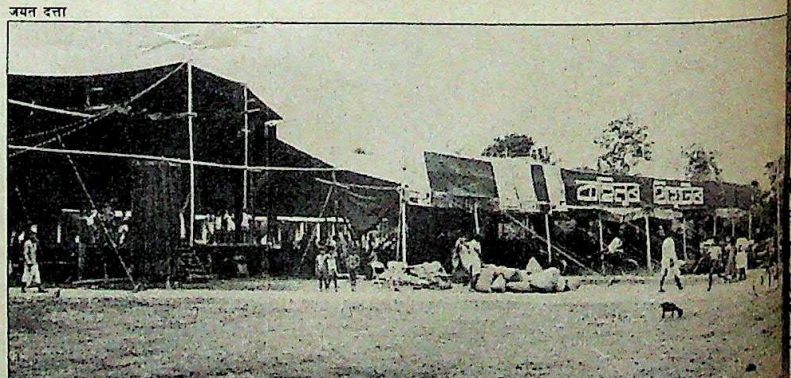

जयंत दत्ता

नाटकों के परिष्कृत और सुरुचिपूर्ण होने का एक कारण यह भी है कि इनके लेखन और निर्देशन से कई सुपरिचित साहित्यकार जुड़े हुए हैं. इनमें साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता डॉ. भावेंद्रनाथ सैकिया, महेंद्र बारठाकुर, अरुण शर्मा, कुलुदा कुमार भट्टाचार्य, दुर्गेश्वर बारणखुर तथा हेमंत दत्ता जैसे सुपरिचित नाम शामिल हैं.

लेकिन इन थिएटरों का संचालन काफी दुरुह है. कलाकार, लाईटिंग व्यवस्था रसोइए, इलेक्ट्रीशियन तथा मजदूरों के अलावा मंच सज्जा के उपकरणों तंबू आदि को भी जल्दी-जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना पड़ता है, जो काफी कष्टप्रद है. चूंकि असम में बिजली बार-बार गुल होती रहती है, सो जेनरेटर भी मंच सज्जा के आवश्यक उपकरण बन गए हैं.

इसी सुनियोजित व्यवस्था का परिणाम है कि प्रत्येक ग्रुप हर सीजन में 7 लाख रुपए की पूंजी पर दो से चार लाख रुपए तक का मुनाफा कमा लेता है. बैंक भी इन्हें बिना सहायता देने में नहीं हिचकते.

इस मोटे मुनाफे से [illegible] आलोचनाओं की पुष्टि हुई कि इन थिएटरों का उद्देश्य महज पैसा कमाना है. सामाजिक उद्देश्य इनके [illegible] नहीं है. थिएटरों ने इन आलोचनाओं के प्रत्युत्तर में कुछ सामाजिक कार्य भी आरंभ कर दिए हैं. आवाहन ग्रुप 'भूमि' नाटक का मंचन कर [illegible]

नाटक का मंचन (बाएं); मंचन से पहले की तैयारी (नीचे): लोकप्रिय आयोजन

हाल ही में इन थिएटरों में से एक ग्रुप ने डॉ. भावेंद्रनाथ सैकिया द्वारा लिखित नाटक में आतंकवाद की निरर्थकता दर्शाया गया है. एक और ग्रुप 'हेतुक' ज्योति प्रसाद अग्रवाल का नाटक 'लिगिरी' मंचित करने का प्रस्ताव [illegible] इस नाटक की गिनती असम के श्रेष्ठ [illegible] में की जाती है. कोहिनूर ग्रुप पहली बार लक्ष्मीनंदन बोरा द्वारा लिखित 'राजा' व्यंग्य 'पाताल भैरवी' का मंचन कर [illegible]

इसमें कोई संदेह नहीं कि समय बीतने के साथ-साथ यह आंदोलन सिर्फ मनोरंजन मात्र न रहकर बेहतर रूप भी धारण कर जाएगा.

—रमेश मेनन, गुवाहाटी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शैक्षिक टीवी

मंजिल मिलेगी मुश्किल से

राजनैतिक नीति निर्धारकों के असमंजस में उलझा एक कार्यक्रम

अहमदाबाद के उपनगरों में दो पाली वाले एक छोटे-से स्कूल में 11-11 वर्ष के करीब 40 बच्चे साधारण-सी बेंचों पर बैठे चुपचाप कलर टीवी देख रहे हैं. हालांकि कार्यक्रम फिल्म्स डिवीजन के औसत दर्जे के किसी शो जैसा है, कि गन्ने से चीनी कैसे बनती है, फिर भी उन्हें आनंद आ रहा है.

पड़ोसी खेड़ा जिले में, जहां गांवों में देश भर के दूसरे जिलों की तुलना में ज्यादा टीवी हैं, दूरदर्शन के जरिये शिक्षा के प्रति बेहद उत्साह पाया जाता है. महादेवपुरा प्राइमरी स्कूल के शिक्षक रणछोड़भाई गणेश रावरी बताते हैं कि स्कूल के सभी 70 बच्चे रोजाना कार्यक्रम देखा करते थे, पर कुछ दिन पहले टीवी टूट गया. उनके सहकर्मी 50 वर्षीय शंकरभाई मकवाना कहते हैं कि इन कार्यक्रमों में औपचारिक बातचीत कम और नाटकीयता थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए.

दूरदर्शन के जरिये शिक्षा का महत्व उजागर हो रहा है. सरकार भी यह जानती है. इसलिए वह अब 4-5 वर्षों के भीतर पूरी तरह शिक्षा के लिए समर्पित टीवी चैनल बनाने की योजना पर गंभीरता से विचार कर रही है.

उधर यह भी संभव है कि इन कार्यक्रमों को कम ही लोग देखें, जैसा कि पिछले महीने अहमदाबाद में बच्चों के एक शैक्षिक वीडियो उत्सव में देखने में आया. सभी कार्यक्रम सरकारी एजेंसियों ने तैयार किए थे और किसी विशेष पाठ्यक्रम के तहत नहीं बनाए गए थे. उनका मकसद 'अधिक ज्ञान' देकर बच्चों को शिक्षित करना था. लेकिन ये कार्यक्रम पाठ्यपुस्तकों से ही बंधे रहे. पर सभी नहीं. मसलन 'हवा', जिसने हाल ही में एनएचके (जापानी टीवी) पुरस्कार जीता, बढ़िया ढंग से तैयार किया गया था. मगर इसमें भी 'उपदेशात्मक' शैली झलकती थी. कुछ दूसरे कार्यक्रम वैचारिक दृष्टि से श्रेष्ठ थे पर पहाड़ी ढलान पर खेलते एक मसखरे के जरिये विभिन्न आकृतियां दर्शाने वाले 'गोल' में कैमरे और रंगों की दृष्टि से कई खामियां थीं. एक और उत्कृष्ट कार्यक्रम 'कैसी होती हैं आवाजें' की तरह यह भी नौसिखिया अभिनय के कारण अपना कोई विशेष प्रभाव नहीं छोड़ पाया.

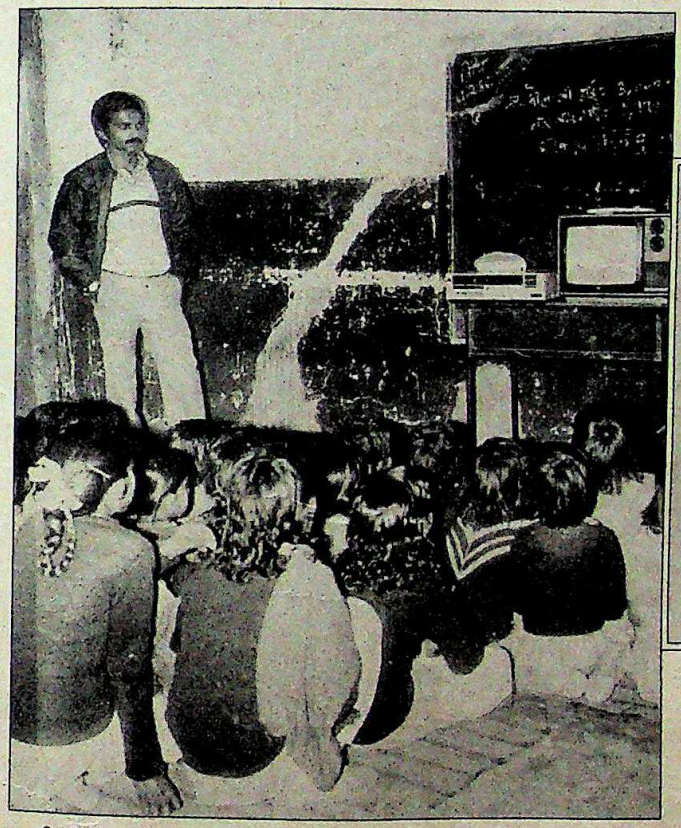

टीवी देखते बच्चे: सम्मोहन

शैक्षिक कार्यक्रमों में खामियों का सारा दोष निर्माताओं या पटकथा लेखकों का नहीं है. आखिर कुछ हद तक इसकी जिम्मेदारी राजनैतिक नीति निर्धारकों की भी है जिन्हें 1983 में ही आकर शैक्षिक टीवी की महत्ता का बोध हुआ. तब यह माध्यम शक्तिशाली ढंग से उभरकर सामने आ चुका था. नई तकनीक के बलबूते, अफसरशाही से लदे पुराने कार्यक्रमों के आधार पर ही, सरकार ने अंतरिक्ष युग में पहुंचने के ख्वाब दिखाने शुरू कर दिए. ऐसे केंद्र स्थापित किए गए जिन्हें वस्तुतः पहले दिन से ही कार्यक्रम तैयार करने के आदेश दिए गए. आश्चर्य नहीं कि उनमें कुछ अफसरशाही के बोझ से दबे अभी भी अपने पांवों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) की एक शाखा सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी (सीआइईटी) के अध्यक्ष प्रोफेसर एम.एम. चौधरी कहते हैं, "हमने तो 1976 और 1983 के बीच के साल गंवा दिए." दूसरे मायने में 'साइट' प्रयोग के, जिसमें देश के छह अत्यधिक पिछड़े जिलों में शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए एक अमेरिकी उपग्रह इस्तेमाल किया गया, आगे कोई और कार्रवाई नहीं की गई.

दरअसल समस्या यह है कि व्यापार बुद्धि वाले इस युग में कोई भी देहात के गरीबों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता. निजी क्षेत्र को कार्यक्रम प्रायोजित करने में रुचि तो है पर मूलतः वे शहरी बच्चों के लिए होते हैं जिससे प्रायोजकों के खिलौनों या दूसरी चीजों के प्रति ललक बढ़े. मगर ऐसे कार्यक्रम भी हैं जो आयात के लिए उपलब्ध हैं. कुछ तो भारी शैक्षिक महत्व के हैं. लेकिन उन्हें आयात करने की लागत बहुत ज्यादा है. शिक्षा सचिव अनिल बोरडिया का कहना है कि जहां जरूरी है वहां के लिए अच्छे विदेशी कार्यक्रम दिखाने में उन्हें कोई एतराज नहीं है. पर साथ ही वे यह भी स्वीकार करते हैं कि भारतीय कार्यक्रम तैयार करने के लिए भी "हमारे पास समुचित प्रतिभा और क्षमता है."

शिक्षा के क्षेत्र में टेलीविजन की उपयोगिता कितनी है यह बिलकुल साफ है. लेकिन सरकार ने इस मामले में कुछ ऐसी नीति चला रखी है कि मामला आगे बढ़ नहीं पा रहा है

हालांकि यह बात सही हो सकती है पर इस पेशे की बेहतर प्रतिभाएं ग्रामीण बच्चों के शैक्षिक कार्यक्रम बनाने के लिए शायद ही

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आगे आई हैं. यही वजह है कि सरकार इस 'अनचाहे बच्चे' का पालन-पोषण करने को मजबूर हुई है और चूंकि उपग्रह के ट्रांस-मिशन का नियंत्रण नई दिल्ली के हाथ में है, इस वजह से राज्य सरकारों को भी लगता है कि शैक्षिक कार्यक्रम चलाने की सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की ही है.

नतीजतन शैक्षिक कार्यक्रम चलाते रहने की सारी जिम्मेदारी केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय और उससे संबद्ध विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और एनसीईआरटी जैसी संस्थाओं पर ही आ गई है. वैसे इन संस्थाओं के सूत्रधार काबिल लोग हैं और बेहतर फैसले भी कर सकते हैं पर उन पर अमल किया जाना एक अलग ही मामला है. इस दिशा में

पूरा मामला इसलिए भी उलझ गया है कि कुशल और पेशेवर लोग गांवों के बच्चों की रुचि और समझ के टीवी कार्यक्रमों को बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं

आयोग और सीआइईटी को तो कुछ कामयाबी मिली है लेकिन आधुनिकतम और महंगे उपकरणों से सज्जित शैक्षिक तकनीकी के राज्य संस्थानों (एसआइईटी) को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. कार्यक्रम के विकेंद्रीकरण का विचार तो बढ़िया है क्योंकि इससे प्रत्येक राज्य के केंद्र को क्षेत्रीय भाषा में कार्यक्रम तैयार करने का मौका मिल जाएगा. लेकिन यह योजना विभिन्न राज्य सरकारों के हाथों में होने के कारण इसके अमल में देरी हो रही है.

एक भी राज्य संस्थान के अध्यक्ष पद पर किसी मीडिया विशेषज्ञ को नियुक्त करने की जरूरत नहीं समझी गई. बोरडिया के इस दावे के बावजूद कि सरकार अध्यक्ष पद पर युवा, उत्साही और कल्पनाशील लोगों को लाने की इच्छुक है, राज्य शैक्षिक परिषद से प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी ही अध्यक्ष पदों पर जमे हुए हैं. लेकिन यह भी सच है कि सरकार इन संस्थानों को चाहे जिस ढांचे पर चलाए, वर्तमान वेतनमान पर तो उसे प्रतिभाशाली लोग मिलने से रहे.

कर्णिक के अनुसार देश में कम-से-कम 500 वीडियो कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने की जरूरत है जबकि डीईसीयू केवल 50 प्रशिक्षणार्थी ही तैयार करता है. 3 से 6 महीने का कोर्स पूरा करके आने वाले इन प्रशिक्षुओं को वीडियो तकनीकी का आरंभिक ज्ञान ही होता है. फिल्म और टेलीविजन संस्थान भी कई लोगों को प्रशिक्षण देता है पर वे सभी दूरदर्शन में लगे हुए हैं.

दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया ही ऐसा संस्थान है जहां टीवी और फिल्म

टीवी कार्यक्रम के लिए अभिनय करते बच्चे

निर्माण के स्नातकोत्तर कोर्स की व्यवस्था है. लेकिन चार वर्षों में 50 छात्र ही इस संस्थान ने तैयार किए हैं. उनमें भी अधिकांश को व्यावसायिक संस्थान झपट लेते हैं.

तमाम प्रयासों के बावजूद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक महीने में केवल दस घंटे के ही कार्यक्रम तैयार कर पाता है. सीआइईटी और एसआइईटी तो और भी कम कार्यक्रम तैयार करते हैं. इसके विपरीत कर्णिक का अनुमान है कि यदि प्रस्तावित शैक्षिक चैनल पर 13 भाषाओं में एक-एक घंटे का प्रसारण शुरू किया गया तो हर महीने करीब 300 घंटों के कार्यक्रम की जरूरत पड़ेगी. इतने लंबे कार्यक्रम की उम्मीद रखना निश्चय ही ज्यादती है. शायद यही कारण है कि सरकार इस नए चैनल को शुरू करने में हिचक रही है. वर्तमान प्रोडक्शन केंद्रों के साथ एक शैक्षिक मीडिया संस्थान बनाने की भी योजना है

बच्चों के लिए क्षेत्रीय भाषा में कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए. बोली की भिन्नता के कारण एसआइईटी के कार्यक्रम समूचे राज्य में नहीं समझे जाते. कर्णिक का सुझाव है कि हरेक राज्य में तीन छोटे केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए जो दो आउटडोर कैमरों और संपादन सुविधा से लैस हों. एक केंद्र की स्थापना पर कुल 15 लाख रुपए खर्च होंगे.

लेकिन एक सफल शैक्षिक चैनल की सफलता के लिए जरूरी है कि वह देश के दूरदराज इलाकों तक पहुंच सके. हालांकि देश में टीवी ट्रांसमीटरों का जाल बिछा हुआ है पर देश भर में केवल एक करोड़ लाख रिसीवर यानी टीवी ही हैं. इनमें भी एक-तिहाई बंबई और दिल्ली पर निर्भर हैं. कर्णिक का अनुमान है कि देश के केवल 10 प्रतिशत परिवारों के पास ही टीवी है 10 से 15 प्रतिशत परिवार पड़ोसियों के सामुदायिक केंद्रों पर टीवी देखते हैं.

कक्षाओं में दिखाए जाने वाले ये कार्यक्रम निश्चय ही लाभप्रद होते हैं. के पांच लाख प्राथमिक स्कूलों को मुहैया कराना काफी कठिन काम है केवल एक लाख स्कूलों को ही टीवी करने की योजना है. लेकिन यदि 1991 तक प्रत्येक स्कूल में एक टी उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर विचार तो हैरानी नहीं होनी चाहिए. यह भी नहीं. लेकिन शैक्षिक टीवी की जरूर थोड़ी कठिन है जिसके लिए उच्च पर राजनैतिक प्रतिबद्धता बहुत जरूरी

—डेविड देवदास, अहमदाबाद और

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कहानी संग्रह

कूची की उदासी कलम से

अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चित्रकार का अकेलेपन का ब्यौरा

दीमक तथा अन्य कहानियां
कहानी संग्रह
रामकुमार
भावना प्रकाशन, रेवती कुंज, हापुड़-245101
कीमत 35.00 रुपए.

शिमला में जन्मे रामकुमार का नया सात कहानियों वाला 'दीमक तथा अन्य कहानियां' संग्रह आया तो एक सुखद आश्चर्य हुआ कि उन्होंने हिंदी कहानी का रास्ता नहीं छोड़ा है. यह अवश्य कहा जा सकता है कि चित्रकला पर अपेक्षाकृत अधिक काम करने से उन्हें भारत के अग्रणी चित्रकारों में गिना जाता है.

चित्रों की दुनिया में रामकुमार को 'उदासी का चितेरा' कहा जाता है. यही 'उदासी' रामकुमार के कथाकार को भी अपनी गिरफ्त में लिये हुए है. उनकी कहानियों को पढ़ते हुए कई बार लगता है कि उदास होने को अभिशप्त इन पीछे छूट गए पात्रों पर लिखना उनके कलाकार का ही एक हिस्सा है. कंट्रास्ट पैदा करते हुए ये कुछ रोमांटिक या शांतिमय कहे जाने वाले माहौल में— पहाड़ों की निस्तब्धता में प्रायः—जाते हैं, जहां धीर-धीरे वे अपने असमंजस, संदेह, संकोच और आंशिक चेतनाओं को तोड़कर अपनेआप से जूझना चाहते हैं. अपने जीवन में निरंतर घर कर गए एक सच को परे धकेलना चाहते हैं. मगर नहीं! उनका यह जोरदार प्रयास भी खाली जाता है. पात्र अपने भीतर और अधिक एकाकीपन महसूस करता है तथा उल्लास की जगह आती पदचाप फिर से यकायक गायब हो जाती है. इन पात्रों के अपने-अपने सेल्फ हैं और उनके अपने-अपने शेल्फ भी. शेल्फों में सजाने ऐसे मजबूत कि किसी की खोल उतारने की हिम्मत ही नहीं होती. यह केवल रामकुमार के ही वश की बात है कि वह किस पात्र के कितने 'आम रहस्यों' का पाठकों को उद्घाटन करा दे. पाठक पात्र को पूरी तरह से जानने के लिए तरसता है— यह इन कहानियों की खूबी है और सीमा भी. स्त्री-पुरुष का आपसी आकर्षण ही नहीं, समान धर्मा, तत्सम् तथा परास्त लोगों के आपसी परिचय को वांछित अपेक्षाएं सौंपना भी रामकुमार को खूब आता है. अपने वर्तमान के छितरे अंधेरों से ये पात्र जूझ रहे होते हैं मगर भविष्य के घटाटोप अंधेरे को ये नकार भी नहीं सकते. 'नाटक', 'लापता', 'मेजर थामसन के खंडहर', 'दीमक' तथा 'बागडोगरा' कहानियों में रामकुमार की यह कला बहुत सुंदर तरीके से गुंथी दिखाई पड़ती है.

मगर इतनी निराशा, ठहराव के होते हुए भी ये पात्र जीवन से और कई बार जीवन दृष्टि से पलायन, विरोध या चिड़-चिड़ाहट तो दिखाते हैं मगर जीवन की निस्सारता का सहारा लेकर उसे नष्ट करने पर नहीं तुलते, जबकि इन कहानियों में और ऐसी कहानियों में आत्महत्या जैसी उद्दंडता कई बार छलछला सकती है. एक महान कवि ने जैसे एक बार 'चुनौती' स्वीकार करते हुए कहा था कि "हे ईश्वर! तू मुझे उतने दुख नहीं दे सकता, जितने मैं सह सकता हूं." कुछ ऐसा ही एक संकल्प इन पात्रों के साथ भी रहा दीखता है. यह इन कहानियों की मुख्य विशेषता है. 'अनधिकार' तथा 'चितू' कहानी में भी दूसरी कहानियों के साथ-साथ यही गुण मौजूद हैं.

रामकुमार को 'उदासी का चितेरा' कहा जाता है. यही 'उदासी' उनके कथाकार को भी गिरफ्त में लिये है. लगता है अभिशप्त पात्रों पर लिखना उनके कलाकार का ही हिस्सा है

ऐसा लगता है मानो रामकुमार कहानी नहीं लिखते बल्कि वे पात्रों की एक छोटी-सी बस्ती का संचालन करते हैं. पात्रों पर वे अतिरिक्त मुद्दा भी नहीं रखते, मात्र उन्हें घटित होता देखते हैं. पात्र इनके बेऐब होते हैं, ईमानदार. वे आपस में प्यार करना चाहते हैं, एक-दूसरे से मिलना चाहते हैं, अपनी तरह से जीना चाहते हैं, अपने को संप्रेषित करना चाहते हैं...मगर नहीं कर पाते. रामकुमार कहानी का केवल ढांचा ही तैयार नहीं करते, वे उसके रोएं-रोएं का सृजन भी करते हैं. उनकी वर्णन लालसा के एवज में एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है— 'वह मधु को टकटकी लगाए देखे जा रही थीं. बत्तीस साल की यह लड़की जिसके भविष्य का कुछ भी पता नहीं, क्या होगा इसका? एक दिन पीठ पर लटके उसके बालों में कुछ सफेद चांदी के-से तार देखकर वह सहसा कांप उठीं, "शायद तेरे बालों में कोई कीड़ा फंसा है मधु..." यह कहकर पास के उसके बालों में कई सफेद बाल उन्होंने ढूंढ़ निकाले थे. "मेरे बाल सफेद होने लगे हैं अम्मा." मधु ने शांत स्वर में कहा था. "नहीं तो..." वह हकलाते हुए बोलीं, "एक-आध शायद हो." "नहीं अम्मा बहुत-से हैं. पहले मैं चुनकर उन्हें तोड़ देती थी, अब ऐसे ही उन्हें छोड़ दिया है." वह हंसने लगी.' (मेजर थामसन के खंडहर).

रामकुमार की कहानियों में वाकई 'साइलेंसर लगा' हुआ है. उनकी मार में कोई कसर नहीं रहती. मगर पाठक द्वारा इसी 'मार' को सहना एक अनुभव बन जाता है. मानसिक कारा में रहने वाले पात्रों को ये कहानियां हीरोइक नहीं बनातीं, उन्हें हुनरमंदी से साइज-अप करती हैं. अतिरिक्त कला, विचारधारा, संवादों की बाढ़ या धड़कनों का सूखा परोसकर इन कहानियों को 'स्वादिष्ट' नहीं बनाया गया है बल्कि इनमें एक निर्दोष-सी किरकिराहट का सम्मिश्रण किया गया है, इसलिए ये कहानियां आज की आम जिंदगी की दुख-तकलीफों का कई बार सच्चा चित्रण भी करती हैं. सत्य की सूली पर चढ़ने की पीड़ायुक्त गरिमा भी इन कहानियों का पाठक पाता है.

यह बात मजाक में कही जाती है कि रामकुमार और निर्मला वर्मा—दोनों भाइयों ने मिलकर जीवन में एक ही कहानी लिखी है. इस संग्रह को पढ़कर गिरते हुए पत्ते, गिरजे, बियर, बूढ़े, लाल टीन की छतें, चुप्पी...आदि कई चीजें हमें उपर्युक्त कमेंट को भूलने भी नहीं देतीं. विस्तार से तो यह बहस का अलग मुद्दा हो सकता है. मगर यह अवश्य कहा जा सकता है कि शुरुआत में ये कहानियां भले ही निर्मलीय दिखाई पड़ती हों, मगर अंत तक आते-आते ये विशुद्ध रामकुमार और रामकुमार की ही कहानियां हो जाती हैं.

—राजकुमार गौतम

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कहानी संग्रह

इर्द-गिर्द की कहानियां

आम आदमी की व्यथा, आक्रोश और विद्रोह का वर्णन

पोस्टर उखड़ गया!
कहानी संग्रह
मनु शर्मा
प्रचारक बुक क्लब, वाराणसी
पृष्ठ-187, कीमत 12 रु.

साहित्यिक जगत में मनु शर्मा के नाम से परिचित हनुमान प्रसाद शर्मा का कहना है कि "सामाजिक संदर्भों में कहानियां अक्सर मुझसे टकरा जाती हैं. कलम के दायरे में उन्हें कैद भर कर लेना मेरा काम होता है. मैं कभी उसकी तलाश नहीं करता और न कभी उसके फेर में मगज खपाता हूं. एक घटना या दुर्घटना की तरह अनचाहे और अनजाने नितांत अप्रत्याशित रूप से यह घटित होता है."

'पोस्टर उखड़ गया!' में संग्रहित 1962 से लेकर 1986 तक की उनकी कहानियों को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए. इन कहानियों में कुछ अनोखी समानताएं हैं. जैसे लगभग सभी कहानियां लेखक के गृह नगर काशी, बनारस या वाराणसी में घटित हुई हैं, ज्यादातर कहानियों में किसी पात्र की मृत्यु कथ्य को या तो नया मोड़ देती है या उस पर पूर्ण विराम लगाती हैं और कमोबेश सभी कथाओं का केंद्र बिंदु आज का कॉमन मैन है जिसके बारे में लेखक 'मैं' का सहारा लेकर वर्णन करता चलता है. पर जैसा कि बच्चन सिंह ने इस संग्रह की भूमिका में लिखा है, "मनु शर्मा की कहानियों में शहर तो है लेकिन वह हाशिये पर मिलेगा, केंद्र में आदमी है जिसे देखने की लेखक की अपनी दृष्टि है, एक वैश्विक नजरिया है....उनकी कहानियों की मौतें इस देश के संदर्भ में हुई हैं. इसमें आदमी मरते-मरते भी पूरा नहीं मरता. आगे की लड़ाई के लिए नए आदमी को अन्याय के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ हथियार थमा जाता है..."

संग्रह में कुल 12 कहानियां हैं, पर इतनी न भी होतीं तो भी संग्रह अच्छा बन पड़ सकता था. जैसे 'तेरा कौन है' और 'चेहरे' कहानियां अपने उद्देश्य का बहुत धुंधला-सा रूप ही दिखाती हैं. इसी तरह व्यंग्य और फैंटेसी का सहारा लेकर लिखी गई' कहानियां—'महंगू धोबी के कुत्ते' और 'मौत एक बड़े बाबू की' चावल में सफेद कंकड़ की तरह मालूम पड़ती हैं. कोई भी संग्रह निश्चित ही निजता की, वैशिष्ट्य की छाप डालने के लिए निकाला जाता है. ऐसे में आम लेखन अगर उसमें दिखे तो खटकना स्वाभाविक ही है. 'वाल्मीकि जो अब नहीं रहा' कहानी पर सुदर्शन की कहानी 'हार की जीत' की छाया दिखाई देती है. हालांकि ऐसा आभास दूर करने के लिए रानी बहू का धीरोदात्त चरित्र दो-तीन और छोटी-छोटी बातों से उकेरा गया है. पर लगता है इसमें कई कथानक गड्डमड्ड होकर रह गए हैं.

पर 'उड़न खटोला', 'बाहरी बेंचों के लोग और बिरजू की बैसाखी', 'बागी' और 'पोस्टर उखड़ गया' बेहतर बन पड़ी हैं. 'उड़न खटोला' का मुख्य पात्र रमेश है तो

" इस दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं, कुछ भी बुरा नहीं... सुना है, आपका भगवान भी तो यही करता है... पोस्टर खुद लगाता है और उखाड़ भी देता है"

मामूली मजदूर ही, पर पावर हाउस की हड़ताल, फाकाकशी की नौबत और तिस पर अपने नेता के 'बिक' जाने ने उसे दार्शनिक बना दिया है.

'उज्ज्वल चरित्र की देन' में मिथ्या प्रशस्तिगान की आज की परंपरा पर मार्मिक कटाक्ष तो किया गया है पर इसका तानाबाना इतने रहस्यमय अंदाज में क्यों बुना गया यह समझ में नहीं आता. 'बेताल का अनुत्तरित प्रश्न' भी गुत्थी सुलझाने का जिम्मा पाठक पर छोड़ देती है. लेखक बताते हैं कि "आप विश्वास कीजिए, बेताल के अनुत्तरित प्रश्न वाली औरत भी [illegible] मिली थी और फिर मिलने का आश्व[illegible] देकर भी मुझसे नहीं मिली."

इस मुकाबले एकदम भिन्न [illegible] वाली 'बाहरी बेंचों के लोग और बिरजू [illegible] बैसाखी' का संदेश, यानी शोक में [illegible] उल्लास की कहानी कहीं ज्यादा स्पष्ट [illegible] मुखर हैं. युद्ध के समय सामान्य जन [illegible] उत्साह, फिर उससे खौफ भी, जीवन [illegible] मृत्यु, आशा और निराशा का इसमें [illegible] वर्णन किया गया है.

'यह कहानी विमला की नहीं है' के [illegible] में लेखक का कहना था कि "दरअसल [illegible] कहानी संस्कृत के उस अध्यापक की है [illegible] इमरजेंसी के जमाने में नसबंदी का प्रम[illegible] पत्र देने के लिए विवश होना पड़ा [illegible] उसके बाद भी उसकी संतान हुई. [illegible] संतान के भविष्य के सोच का परिणाम [illegible] यह कहानी है." पर कहानी का केंद्र [illegible] कानून, अदालत और यह व्यवस्था [illegible] पड़ती है जिनकी विसंगतियां विमला [illegible] उसके बेटे के माध्यम से उजागर की ग[illegible]

पर संग्रह के नाम वाली कहानी 'पो[illegible] उखड़ गया' में ये विसंगतियां ज्यादा [illegible] तरह उकेरी गई लगती हैं. कथा इस वि[illegible] पर आधारित है कि जीवन भी पोस्टर [illegible] तरह है जिनको कोई अदृश्य हाथ नियति [illegible] दीवार पर चिपका देता है और [illegible] चुपचाप उखाड़ भी लेता है. रामनाथ [illegible] दिन में पोस्टर चिपकाने और रात में [illegible] पोस्टर उखाड़कर पेट भरने वाले लाखों [illegible] इस देश में बसते हैं. उनकी नियति रा[illegible] की ही तरह तो होती है जो खुद भी [illegible] इस दुनिया की दीवार से गुपचुप उतार [illegible] जाते है. पर जब तक वे जीते हैं [illegible] निश्चिंत होकर जीते हैं.

वैसे लेखक पुराणोतिहासकाल [illegible] आधारित उपन्यास रचने में माहिर [illegible] उनके चार उपन्यास—'बाप्पा रावल, [illegible] प्रश्न, 'द्रोण की आत्मकथा' और 'क[illegible] आत्मकथा' बर्मी और उड़िया में भी अ[illegible] हो चुके हैं. और फिर मनु शर्मा खुद मा[illegible] कि "उपन्यास मेरी मुख्य विधा है. [illegible] क्षेत्र में यह पांच दिनों का क्रिकेट है [illegible] कहानी एक दिन का क्रिकेट. मैं [illegible] पांच दिनों के क्रिकेट का ही खिलाड़ी [illegible] हूं." तो एक दिन के इस प्रस्तुत 'क्रिके[illegible] 'बोल्ड' होने की तमाम आशंकाओं [illegible] बावजूद उन्होंने पारी खेली तो है पर [illegible] श्रीकांत की तरह तेज रफ्तार [illegible] प्रभावोत्पादक पारी, तो कभी रवि [illegible] की तरह धीमी-धीमी एक उबाऊ पा[illegible]

—जगदीश [illegible]

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मोनॅको फिर से बड़े पैक में!

छोटे पैक में भी उपलब्ध

पारले
मोनॅको
यूं ही खाएं तो मज़ेदार,
टॉपिंग्ज़ के साथ बेमिसाल.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

everest/87/PP/357 hnR

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मोटोक्रास रेसिंग

दमखम वालों का दबदबा

भारत में इस जोखिम भरे खेल की कामयाबी के आसार

नए खेल के नए शब्द—हूप-डे-डू, बर्म, कैमल जंप, टेबल टॉप, चेस्ट प्रोटेक्टर भारतीय खेल जगत में अपनी जगह बनाने लगे हैं. वजह स्टेडियम मोटोक्रास रेस की बढ़ती लोकप्रियता है. यह एक तूफानी और चमत्कारी खेल है जिसमें तेज गति वाली और मजबूत मोटरसाइकिलों को खास तौर पर कीचड़ से सने मार्ग पर दौड़ाया जाता है.

और नया साल शुरू होते ही भारत में इस खेल को अंतरराष्ट्रीय मान्यता भी मिल गई. पिछले पखवाड़े पुणे के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 17,000 दर्शकों के सामने रोडिल ट्रॉफी स्टेडिटम मोटोक्रास विश्व चैंपियनशिप का पहला दौर आयोजित हुआ. इस धूल-धूसरित शहर से मोटोक्रास के खिलाड़ी अब स्वीडन, हॉलैंड, बेल्जियम और इटली में मोटरसाइकिलें दौड़ाते स्पेन पहुंचेंगे जहां चैंपियनशिप का अंतिम दौर होगा. इंटरनेशनल मोटरसाइकिलिस्ट फेडरेशन के अध्यक्ष तागे मेगनुसन कहते हैं, "मुझे विश्वास है कि पुणे मोटोक्रास की सफलता से भारत में इस खेल को भारी बढ़ावा मिलेगा."

हालांकि क्रास कंट्री मोटरसाइकिल रेसिंग की शुरुआत 50 वर्ष पहले हुई पर पहली स्टेडियम मोटोक्रास रेस 1972 में लॉस एंजिलिस के कोलिसियम में आयोजित की गई. पांच साल बाद भारत की पहली स्टेडियम मोटोक्रास रेस जयपुर में हुई. यह एक उत्कृष्ट बाधा दौड़ है जिसमें मोटर-साइकिल सवारों के कौशल, गति, एकाग्रता और सहिष्णुता की प्रतियोगिता कराई जाती है. कृत्रिम बाधाओं की वजह से इस खेल की एक विशेष शब्दावली गढ़ी गई है. 'हूप-डे-डू' मार्ग में एक साथ कई ऊबड़-खाबड़ जगहों को परिभाषित करता है. 'बर्म' कीचड़ से सना एक पेचीदा मोड़ है. 'कैमल जंप' का अर्थ दुहरी बाधा है. सबसे शानदार 25 फीट ऊंचा 'टेबल टॉप' है जिसे ड्राइवर बेतहाशा रफ्तार से पार करते हैं. इसमें वे हवा में 30 से 40 फुट तक छलांग भरते हैं.

हालांकि करतबबाजी बेहद दंग कर देने वाली होती है पर मोटोक्रास रेस जीतना भी जीवट का काम है. ऐसा ही कमाल स्वीडन के 22 वर्षीय बो ह्योगेबर्ग ने पुणे में दिखाया. उन्होंने अपनी सफेद यामाहा वाईज़ेड-250 की सवारी से रोडिल ट्रॉफी का पहला दौर जीता. इसमें उन्होंने अमेरिका के 20 वर्षीय मोटरसाइकिल सवार जिम 'जेंटलमैन' हॉली समेत पिछले चैंपियन स्वीडन के 28 लीफ निकल्सन को भी हराया. दूसरा गहरे लाल रंग की होंडा सीआर-2 सवार अमेरिका के 25 वर्षीय विल ने जीता जबकि दर्शकों का मन मोह फ्रांस के 22 वर्षीय ओलिवियर पेरी बढ़त दिखाकर तीसरे स्थान पर रहे. शुरू में ही अपनी गहरे पीले रंग की आरएम-250 से गिर पड़े थे.

लेकिन दर्शकों के लिए संतोष की रही कि भारत के एकमात्र प्रतियोगी 17 वर्षीय जगतवीर सिंह ने भी करके रोडिल चैंपियनशिप में देश की

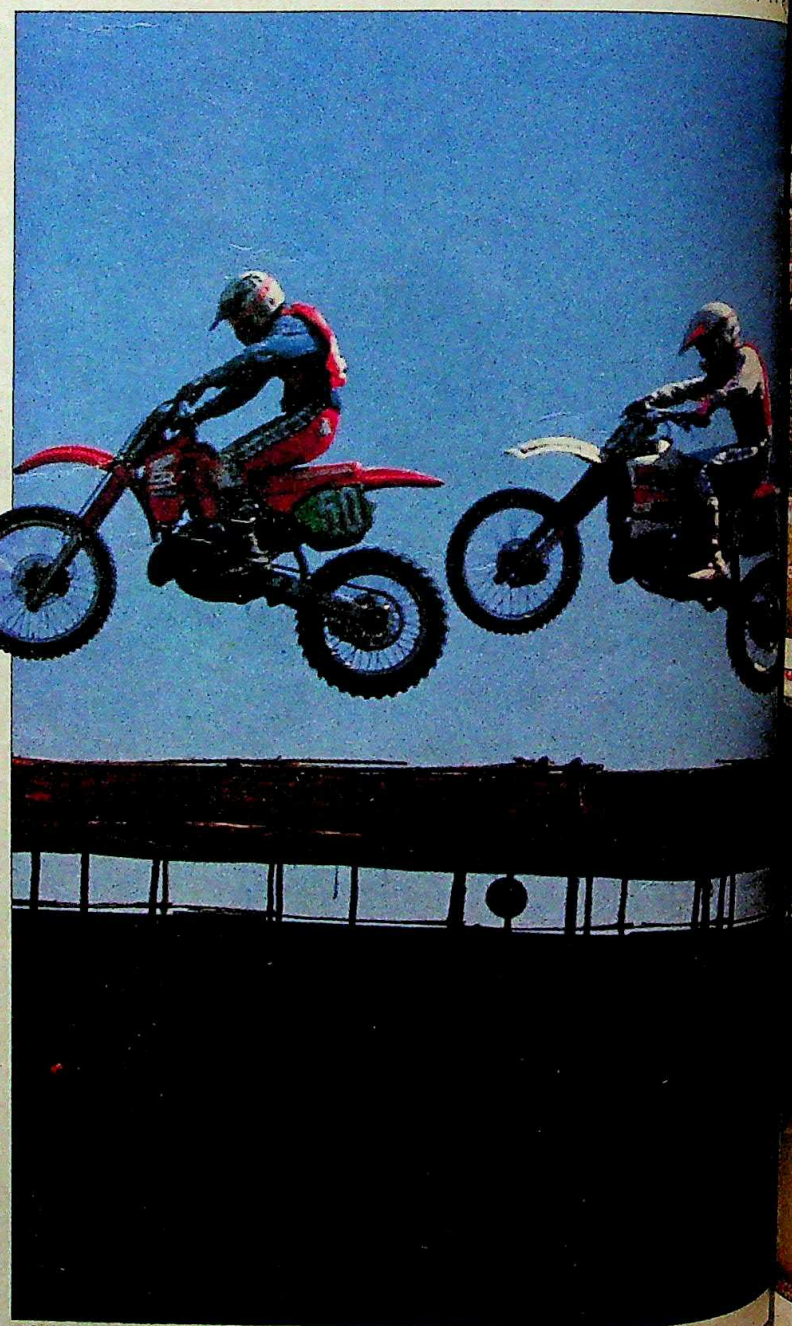

हवा में मसग्रेव (बाएं) और ह्योगेबर्ग

सभी फोटो: तामस भोजानी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

की. वे कहते हैं, "मेरा मुख्य उद्देश्य रेस करना था. अब दसवीं पास करते ही मैं जाकर मोटोक्रास का विधिवत पाने की सोच रहा हूं."

मोटोक्रास की सफलता ने पुणे को इस खेल शुआ केंद्र बना दिया है. शहर में माने गए दो क्लब हैं—पुणे ऑटो-रेसिंग एसोसिएशन (पारा) और ऑटो रेसक्रॉप्टर्स (बार्क). पुणे को आश्रम में दुनिया के माने हुए राइडरों की मौजूदगी का भी मिला है. 'पारा' के जगतवीर सरीखे ने मोटरसाइकिल के रखरखाव और मोटोक्रास रेसिंग की कला रजनीश के अनुयायी आनंद सेमियो से सीखी है. 26 वर्षीय सेमियो चिली के पूर्व चैंपियन हैं. जगतवीर कहते हैं, "सेमियो से प्रशिक्षण पाने से पहले हम तो निहायत अनाड़ी राइडर थे."

मोटरसाइकिल रेस महंगा खेल है. भारत में सीमा शुल्क अदा करने के बाद जापान की 250 सीसी की मोटोक्रास रेसिंग मोटर-साइकिल एक लाख रुपए से भी अधिक में पड़ती है. फिर स्पेयर पार्ट्स के अलावा विशेष प्रकार के हेलमेट, न टूटने वाले धूप के चश्मे, छाती के कवच, एल्बो गार्ड्स, किडनी बेल्ट, शोल्डर पैड और रबड़ के बूटों की जरूरत होती है जो विदेशों में ही उपलब्ध हैं.

उच्च श्रेणी के अधिकांश राइडरों को भारत के दुपहिया वाहन निर्माताओं से यामाहा, होंडा और सुजुकी मोटरसाइकिलों के तोहफे के रूप में मदद मिलती है. बजाज ही एक ऐसी कंपनी है जिसने भारत में इस खेल के भविष्य के मद्देनजर कावासाकी राइडरों की अपनी टीम तैयार कर रखी है. टीम को प्रशिक्षण दिलाने के लिए वह हर साल जापानी विशेषज्ञों को भी पुणे बुलाती है. आश्चर्य नहीं कि बजाज वाली टीम की हरी मोटरसाइकिलों ने नेहरू स्टेडियम की 250 सीसी और 125 सीसी की इंडियन ग्रां प्री रेसों में जीत हासिल की.

मोटोक्रास रेस बहुत ही दमखम वाला खेल भी है. मसलन पुणे में मोटोक्रास के 1.3 किलोमीटर लंबे मार्ग पर करीब 30 बाधाएं खड़ी की गई थीं. इंडियन ग्रां प्री की 125 सीसी और 250 सीसी रेसों के लिए सात-सात चरणों के तीन चक्कर थे और हर चरण पूरा करने में 1.5 मिनट लगता था. यानी कि तीन चक्कर पूरा करने तक इसके हर प्रतियोगी को करीब 600 झटकों और ऊबड़-खाबड़ मोड़ों में से गुजरना पड़ता है.

इंडियन 250 सीसी ग्रां प्री के पहले चक्कर में हालांकि एक राइडर बड़े खतरनाक तरीके से मोटरसाइकिल से गिर गया था पर अंतिम चक्कर के आखिरी क्षणों में ही जाकर मोटोक्रास रेसिंग की उत्तेजना देखने में आई. 'बार्क' के प्रशिक्षक अशरफ शेख के बेटे आरिफ ने एक दुस्साहसिक छलांग में 'पारा' के 21 वर्षीय प्रताप भागवत से आगे निकलने की कोशिश की. ज्योंही आरिफ ने विजेता रेखा की काली-सफेद झंडी पार की वह अपनी कावासाकी से लुढ़क गया. उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. उसकी एक टांग और पसली टूट गई थी. रेस में अव्वल वही रहा.

अब 'पारा' रोडिल विश्व चैंपियनशिप की तर्ज पर एक राष्ट्रीय चैंपियनशिप आयोजित करने का विचार कर रही है. यह राष्ट्रीय चैंपियनशिप इसी साल शुरू की जाएगी. इसके लिए देश में छह दौर आयोजित होंगे. 'पारा' के संयोजक अशोक ग्रोवर बताते हैं कि "लोगों की रुचि स्टेडियम मोटोक्रास में दिनोदिन बढ़ती जा रही है."

अब इसमें कोई संदेह नहीं कि स्टेडियम मोटोक्रास रेस में एक राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के सभी आकर्षण—गति, कौशल, कलाबाजी और रोमांच पूरी तरह मौजूद हैं.

—एम. रहमान

प्रतियोगिता पथ (नीचे); और 'टेबल टॉप' पार करते सवार: जांबाज करतब

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

◆ जुगलबंदी लाजवाब थी और इसकी शास्त्रीय स्वरलिपि कैनवास पर अंकित की गई. इस सामंजस्य को अंजाम दिया चित्रकार **मकबूल फिदा हुसैन** और गायक पंडित **भीमसेन जोशी** ने. जब एक कलाकार तरन्नुम में राग छेड़ता तो दूसरा उसे उसी खूबसूरती से कैनवास पर जीवंत कर देता. दोनों ही दिग्गज बंबई आर्ट सोसायटी द्वारा आयोजित शताब्दी समारोह में इकट्ठे हुए थे. हुसैन ने इसे 'चित्रकारी में संगीत का प्रस्तुतीकरण' की संज्ञा दी. उनके इस सृजन के लिए कार्यक्रम के आयोजकों ने पांच लाख रुपए अदा किए. यह राशि उभरते कलाकारों को दी जाने वाली बेंद्रे-हुसैन छात्रवृत्ति के रूप में प्रयोग की जाएगी. हुसैन कहते हैं, "जोशी महान कलाकार हैं. उन्होंने अपनी पूरी श्रेष्ठता गायन में उतार दी और वह शब्द चित्र के रूप में दर्शनीय है." चित्रकारी के बारे में उनका कहना था, "शब्दों को चित्रों में उतारना उतना ही उत्तेजक है जितना किसी चित्र का पूरा होना. लोगों को दोनों का भरपूर आनंद उठाना चाहिए."

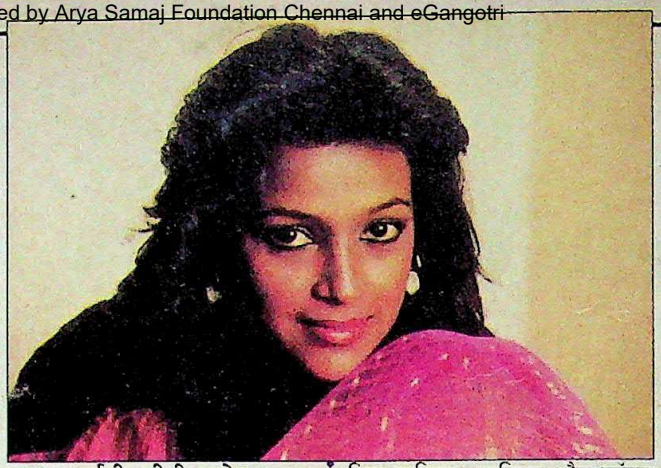

पार्वती: टीवी प्रकोप

◆ ट्रिनीडाड के लोगों के लिए 26 वर्षीया **पार्वती खां** एक लोकप्रिय गायिका, नायिका और मॉडल का नाम है. लेकिन मंडी हाउस के लिए यह नाम अनुपयुक्त है. पार्वती ने टीवी सीरियल 'नई दिशाएं' में सबसे पहले अभिनय किया. दूरदर्शन ने इस सीरियल के निर्माता विवेक वासवानी को सूचित किया कि वह अभिनेताओं की सूची से उनका नाम हटा दे क्योंकि इससे एक दर्शक की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है. पार्वती कहती हैं, "मुझे दूरदर्शन के गैर-जिम्मेदार रवैये से नफरत है." उनके ससुर और फिल्मी पटकथा लेखक राही मासूम रजा भी इससे क्रुद्ध हुए हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री राजीव गांधी और राष्ट्रपति वेंकटरामन तक को पत्र लिखे हैं पर अभी उनका जवाब आना बाकी है. सेंसर की कैंची उनके नाम पर चलने के बावजूद पार्वती अभिनेता गोविंदा के साथ एक पॉप कैसेट के लिए अपनी आवाज दे रही हैं. इसके अलावा उनका गजल और फिल्मी गीत गाने का इरादा भी है.

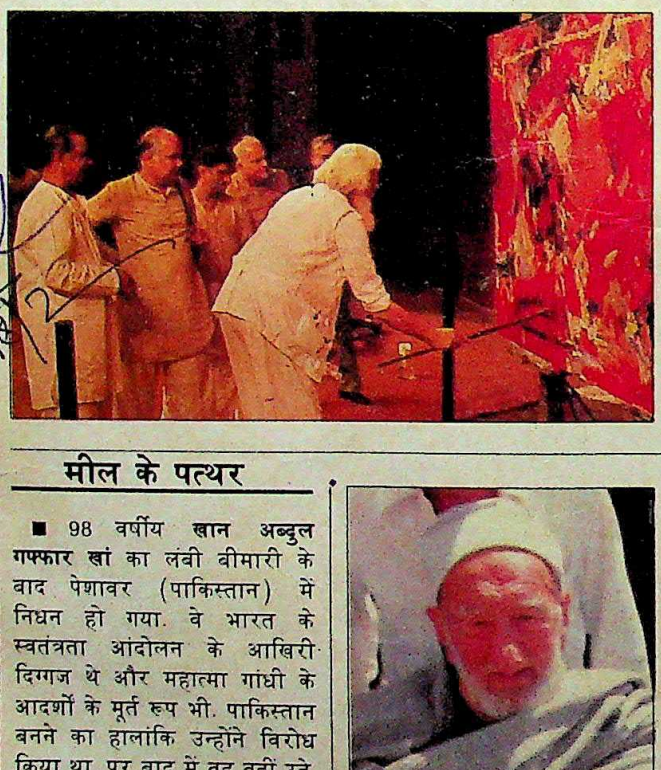

हुसैन: नया शगूफा

◆ "अमूमन लोग फिल्मों के दायरे में निकलकर राजनीति के बड़े दायरे में प्रवेश करते हैं, मैं इससे ठीक उलटा कर रही यह कहना है पश्चिम बंगाल विधायक **सुव्रत मुकर्जी** का बंगला के टीवी सीरियल 'फार्मास्यूटिकल्स' में मुख्य भूमिका अदा कर रहे हैं. कंपनी निदेशक रूप में वह दवा उद्योग में भ्रष्टाचार से टक्कर लेंगे. साथ दे रही है सेक्सी अभिनेत्री जाने वाली **मुनमुन सेन**.

मुकर्जी: परदे पर

मुख्य भूमिका अदा करने और मुनमुन के पारिवारिक भी है. मुनमुन दवा कार भ्रष्ट मालिक की आदर्शवादी की भूमिका में हैं. वे "निर्माताओं को आशा है अभिनय के प्रति सुव्रत की दूर कर दूंगी." लेकिन कहना है, "यह मेरी गतिविधियों का ही एक और इससे मैं लोगों को के प्रति जागरूक भी कर

मील के पत्थर

■ 98 वर्षीय **खान अब्दुल गफ्फार खां** का लंबी बीमारी के बाद पेशावर (पाकिस्तान) में निधन हो गया. वे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के आखिरी दिग्गज थे और महात्मा गांधी के आदर्शों के मूर्त रूप भी. पाकिस्तान बनने का हालांकि उन्होंने विरोध किया था, पर बाद में वह वहीं रहे. अंतिम इच्छा के अनुसार उन्हें अफगानिस्तान के जलालाबाद में उसी मकान में दफनाया गया, जहां वह कुछ अरसे तक रहे थे.

पख्तूनों के अधिकारों को लेकर बादशाह खां ने 15 साल पाकिस्तानी जेलों में गुजारे. उनके द्वारा 1929 में गठित लाल कुर्ता खुदाई खिदमतगार संगठन पर पाकिस्तानी सरकार ने रोक लगा दी थी. जेल से छूटने के बाद वे आठ वर्ष तक अफगानिस्तान में खुद निर्वासित रहे. लेकिन वे अहिंसा, व्यक्तिगत स्वाधीनता और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए आजीवन संघर्ष करते रहे. गांधी के मूल्यों को उन्होंने आत्मसात कर लिया था. पिछले साल उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया था.

सीमांत गांधी: योद्धा

■ प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, कुशल प्रशासक और राज्यसभा के सदस्य 74 वर्षीय **लक्ष्मीकांत झा** का गुर्दे की खराबी के कारण निधन हो गया. व्यावहारिक और कार्यकुशल झा वर्तमान प्रधानमंत्री के बेहद करीबी लोगों में से थे. वे उदारवादी नीति के हामी थे. उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर और विभिन्न आर्थिक आयोगों के प्रधान रहने पर ऐसी अनेक नीतियों को लागू भी किया.

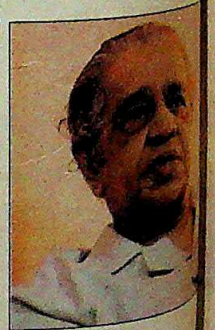

झा: कार्यकुशल

एक सक्रिय कूटनीतिज्ञ के बांग्लादेश युद्ध के दौरान में भारत के राजदूत और 1981 तक जम्मू-कश्मीर पाल भी रहे.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

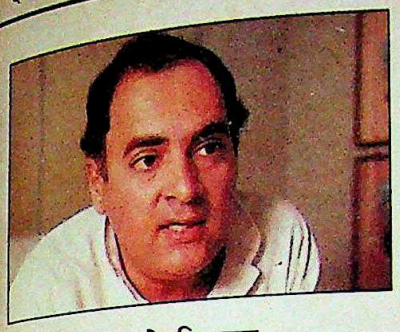

नया रूप, बदलते मिजाज

प्रधानमंत्री बनने के तीन वर्षों के भीतर ही राजीव बदल गए हैं. शारीरिक और राजनैतिक रूप से तथा आचार-व्यवहार के तौर पर भी. युवा प्रधानमंत्री में आए इन बदलावों का विस्तृत विश्लेषण और साथ में देश के मानस को मापता खास जनमत सर्वेक्षण.

आवरण कथा 14

इंका की बदली किस्मत

त्रिपुरा में उग्रवादियों द्वारा की गई हत्याओं से घबराए मतदाताओं ने सत्तारूढ़ माकपा को उखाड़ फेंका. उधर पड़ोसी राज्य मेघालय में भी अल्पमत पाने के बावजूद इंका ने सत्ता की बागडोर संभाल ली. दोनों राज्यों का चुनाव विश्लेषण.

विशेष चुनाव रपट 28

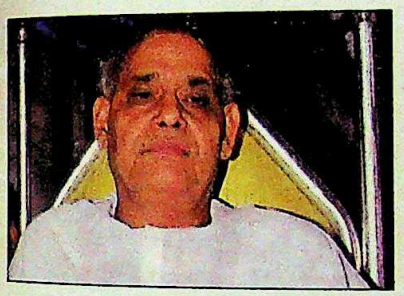

दांव पर लगे मोहरे

अब से पहले मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिलने के लिए दिल्ली में इस तरह लाइन में नहीं लगा करते थे और न ही इस कदर अपमानित हुआ करते थे. हालात अब बहुत बदल गए हैं. राज्यों में नेतृत्व बदल की राजीव-दरबार की रणनीति पर रिपोर्ट.

आजकल 34

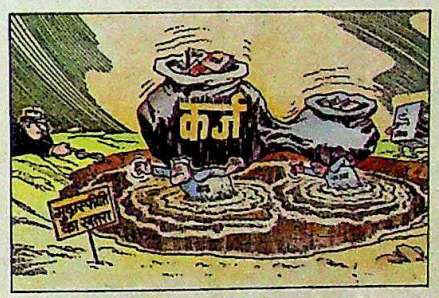

फंदे में फंसी अर्थव्यवस्था

वर्षों से देश और विदेशों से अंधाधुंध कर्ज लेने की सरकार की नीति ने देश को कर्ज के फंदे में धकेल दिया है. कर्ज की बढ़ती देनदारियों के साथ-साथ संकट के साये हर भारतीय पर मंडराने लगे हैं. अब हिसाब-किताब चुकता करने की घड़ी आ पहुंची है.

कारोबार 62

नरभक्षी बाघों का कहर

पश्चिम बंगाल के सुंदरवन के निवासी नरभक्षी बाघों के आतंक से बुरी तरह त्रस्त हो चुके हैं. वहां जीवन इतना अनिश्चित हो चला है कि सुबह मछली पकड़ने के लिए निकले मछुआरों के परिवार वालों को भरोसा ही नहीं रहता कि दुबारा वे उन्हें देख पाएंगे या नहीं.

छाया लेख 78

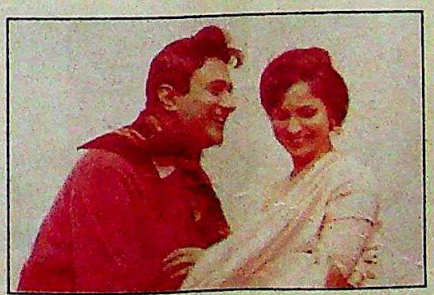

दूसरी पारी में भी जमीं

पिछले कुछ महीनों से साठ और सत्तर के दशक की फिल्मों का दौर एक बार फिर लौट आया है. आज की भौंडी और ऊबाऊ फिल्मों से दर्शक मानो एकदम उकता गए हैं. सिनेमाप्रेमी अब फिर उन पुरानी संगीतमयी फंतासियों की ओर उमड़ पड़े हैं.

सिनेमा 90

अगले पन्नों पर

कसौटी 9
तेवर 10
राजरंग 11
हिंदोस्तां हमारा 12
बीता पखवाड़ा 13
आवरण कथा
राजीव गांधी:
नया रूप, बदलते मिजाज 14
जनमत संग्रह: विकल्प की कमी 21
विशेष चुनाव रपट:
त्रिपुरा: इंका की बदली किस्मत 28
मेघालय: बैसाखी पर टिकी सरकार 31
आजकल
इंका मुख्यमंत्री: दांव पर लगे मोहरे 34
सरकारिया आयोग: नपी तुली रपट 37
उत्तर प्रदेश: अद्भुत शक्ति प्रदर्शन 38
राजस्थान: दिग्गजों से मुंह मोड़ा 40
तमिलनाडु: बढ़ती उलझन 45
गोरखा आंदोलन: समझौते का संकट 47
उत्तर प्रदेश: दहेज की बलि 49
आंध्र प्रदेश: विवाद के घेरे में 50
पंजाब: बदला पैंतरा 52
आखिरी बात 53
विशेष लेख
मुस्लिम महिला कानून:
निगलते बने न उगलते 54
राज्य दर्पण 57
पास-पड़ोस
श्रीलंका: वक्त बहुत कम है 58
व्यापार-चक्र 61
कारोबार
राष्ट्रीय कर्जे: फंदे में फंसी अर्थव्यवस्था 62
डीसीएम: आखिरी मौका 66
मध्य प्रदेश: चमक धुंधलाई 68
विकास
सूरजकुंड मेला: लोककलाओं का झरोखा 72
टीवी
तमस: विवादों की चांदमारी 74
खेलकूद
क्रिकेट: मैदान के बाहर मुकाबला 76
छाया लेख
सुंदरवन: नरभक्षी बाघों का कहर 78
स्वास्थ्य
बाल रोग: सुविधाओं का अकाल 88
सिनेमा
पुरानी फिल्में: दूसरी पारी में भी जमीं 90
रथाथिन रथामे: परदे पर नया प्रयोग 91
किताबें 94
समाचार माध्यम
उत्तर प्रदेश: 'आज' का 'जागरण युद्ध' 96
आबोहवा
कानपुर: गंगा एक, भगीरथ अनेक 97
पश्चिमी घाट: बंजर पहाड़ों की परिक्रमा 99
चर्चित चेहरे 104

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सवारी हो तो एटलस. जो करे हवा से बातें

5-स्पीड वाली नई स्पोर्टस्टर

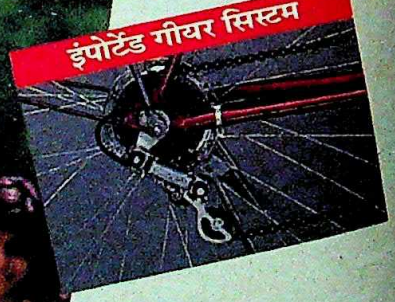

- सर्वोपेन्टा प्रणाली से युक्त आयातित सन रेस गीयर सिस्टम
- गीयर 1 तथा 2: सवार हो जाइये और कीजिए हवाई सफ़र शुरू. सामने की हवा हो या कोई पहाड़ी सफ़र

  गीयर 3: दौड़ाइये तेजी से, समुद्र तट की राहों पर
- अब आइए चौथे गीयर में और बढ़ाइए अपनी स्पीड
- गीयर 5: और दौड़ाइए अपनी साइकिल एक चैम्पियन की तरह
- विशेषरूप से डिज़ाइन किया गया फ्रेम! सुगम गीयर परिचालन के लिए
- एक्रीलिक : पोलीक्रोमेटिक रंग—गहरा जामुनी (बरगंडी)नीला, कत्थई, सलेटी

एक और सनसनीखेज़ साइकिल

ऐच्छिक सुविधा : विशिष्ट टैकोमीटर
5 स्पीड वाली स्पोर्टस्टर चुनिए या स्पोर्टस्टर

IMPORTED
5 SPEED GEAR SYSTEM
SUNRACE
ATLAS

Atlas
«FUNFLEET»

विश्व श्रेणी विश्व शैली की साइकिलें

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Foundation Chennai and eGangotri

नाश्ते की संगत स्वाद की रंगत

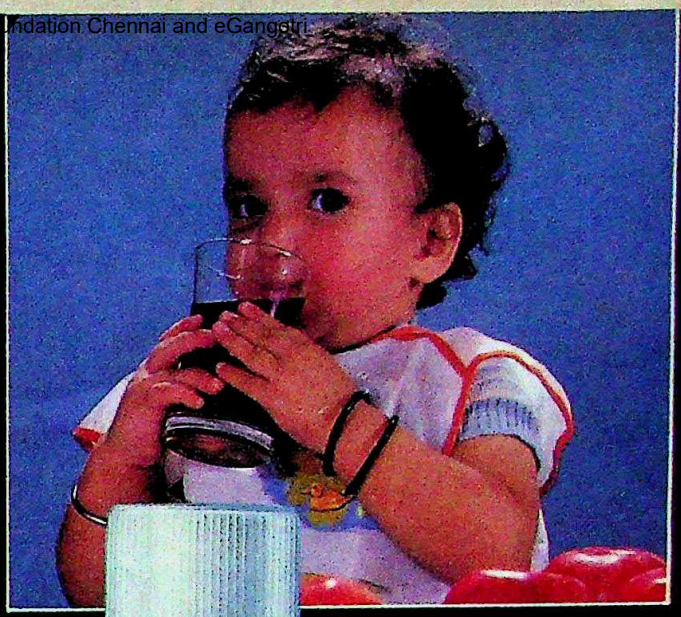

नयी सुबह की शुरुआत.
फिर वही काम, फिर वही भागमभाग.
ऐसे में कहां फुरसद दिन-भर के लिए
ताजगी देने वाला पहला-पहला नाश्ता लेने की.
लेकिन ऐसे मौके पर ही तो आपको चाहिए
चुस्ती-फुर्ती देने वाला ठंडा शीतल पेय.
नाश्ते के संग जो जमा दे रंग!

और क्या हो सकता है?
7 इन 1. के सिवाय

डालिए, मिलाइए, चुसकिए. दिन-भर चुस्त रहिए.

उत्पादन संबंधी जानकारी:

- *100% प्राकृतिक, कोई प्रिज़र्वेटिव या एडीटिव नहीं.*
- *इसे घोलकर 8 गुना ज्यादा बनाया जा सकता है.*
- *प्राकृतिक मीठा स्वाद, चीनी की ज़रूरत नहीं.*
- *सेब के सभी पौष्टिक गुणों से भरपूर.*
- *हर तरह के व्यंजन बनाने के लिए स्वास्थ्यकर.*

himachal
hpmc
(सरकार का एक उपक्रम)
हिमाचल प्रदेश हॉर्टीकल्चर, प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कार्पोरेशन लि.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

टाटा की ओर से टाइटन क्वार्ट्ज़

ऐसी घड़ियों के लिए अब आपको यूरोप, जापान अमरीका या किसी ड्यूटी-फ़्री दुकान में जाने की ज़रूरत नहीं. इन्हें आपके शहर में पेश कर रहे हैं टाइटन.

आकर्षक, पतली और बहुत बारीक इंजीनियरिंग से सजी संवरी टाइटन घड़ियां दुनिया की सबसे अच्छी घड़ियों की बराबरी में आ सकती हैं.

टाइटन की **अंतर्राष्ट्रीय किस्मों** में ऐसी घड़ी ज़रूर है, जो आपके लिए बिल्कुल सही है. शान और रूप का अनोखा संगम. लेदर के साथ गोल्ड वाली टाइटन या सिर्फ़ गोल्ड की चमकदमक वाली लीजिए. अगर सिर्फ़ स्टील वाली चाहिए तो वो भी हाज़िर. या फिर आजकल के ज़माने वाली कोई और टाइटन चुन लीजिए.

महिलाओं के लिए निहायत खूबसूरत डिज़ाइनों वाला कलेक्शन, जिसमें स्टाइल, वरायटी और रंगों पर विशेष नज़र रखी गई है. इतना ही नहीं, टाइटन के पास लेडीज़ डेट और डे-डेट घड़ियों की सबसे बड़ी श्रेणी मौजूद है.

टाइटन क्वार्ट्ज़ अपनी बराबरी में आ सकनेवाली सबसे अच्छी, चाबी से चलने वाली या आटोमैटिक घड़ियों से **६० गुना ज़्यादा सही** है.

हर टाइटन क्वार्ट्ज़ पर क्वालिटी और विश्वसनीयता की **टाटा गारण्टी** है.

अपने शहर की किसी अच्छी घड़ी की दुकान में जाइए और पसंद कीजिए कोई टाइटन क्वार्ट्ज़ अपने लिए या अपनों के लिए.

TITAN
QUARTZ

अपने लिए, अपनों के लिए

शानदार स्टाइल वाली टाइटन घड़ियां केवल रु. ३६२ से रु. ११३७ (बिक्री कर और स्थानीय कर अलावा) तक में मिलती हैं.

टाइटन वाचेज़ लिमिटेड
सोना टावर्स, ७१ मिलर रोड, बंगलोर ५६० ०५२.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इंडिया टुडे
संपूर्ण समाचार पत्रिका

वर्ष 2, अंक 8, 16-29 फरवरी, 1988

प्रधान संपादक: अरुण पुरी
वरिष्ठ संपादक: प्रभु चावला

लिविंग मीडिया इंडिया प्रा. लि., एफ-14 कंपिटेंट हाउस, कनाट प्लेस, नई दिल्ली के लिए अरुण पुरी द्वारा संपादित और प्रकाशित तथा थॉमसन प्रेस इंडिया लि. फरीदाबाद, हरियाणा में मुद्रित.

संपादकीय कार्यालय:
लिविंग मीडिया इंडिया प्रा. लि., एफ-14/15, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001. फोन: 331 5801-4, टेलेक्स: 31-61245 INTO IN, तार: लिवमीडिया नई दिल्ली.

मुख्य सर्कुलेशन कार्यालय:
इंडिया टुडे सर्कुलेशन मैनेजर, एफ-14, कंपिटेंट हाउस, कनाट प्लेस, मिडल सर्कल, नई दिल्ली-110001. फोन: 3313076-8, टेलेक्स: 31-62634 INTO IN, तार: सर्कुलेट, नई दिल्ली.

मुख्य विज्ञापन कार्यालय:
28 ए और बी, जॉली मेकर चैंबर-2, नरीमन पाइंट, बंबई-400021. फोन: 2026152, 2029326, 2029435, टेलेक्स: 11-5373 THOM IN, तार: लिवमीडिया बंबई.

क्षेत्रीय विज्ञापन कार्यालय:
के-9, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001, फोन: 352378, 323576, 351273, 351323; टेलेक्स: 31-62124 THOM IN, तार: लिवमीडिया, नई दिल्ली; फागुन चैंबर्स, 26 कमांडर-इन-चीफ रोड, मद्रास-600105. फोन: 477188, 477770, टेलेक्स: 041-6177 INTO IN, तार: लिवमीडिया, मद्रास; 74/1, सेंट मार्क्स रोड, बंगलूर-560001. फोन: 568448, 579037, 579089, टेलेक्स: 0845-2217 INTO IN, तार: लिवमीडिया, बंगलूर; 12-सी, एवरेस्ट 46-सी, चौरंगी रोड, कलकत्ता-700016 फोन: 445398, 447726, टेलेक्स: 021-3138 INTO IN, तार: लिवइन-मीडिया, कलकत्ता.

कॉपीराइट 1984 लिविंग मीडिया इंडिया प्रा. लि. विश्व भर में सर्वाधिकार सुरक्षित. किसी भी रूप में सामग्री की नकल प्रतिबंधित. इंडिया टुडे अनिमंत्रित प्रकाशन सामग्री को लौटाने की ज़िम्मेदारी स्वीकार नहीं करता.

नेपाल में 6 रुपए

उच्चवर्गीय तमन्ना

आवरण कथा 'तंदुरुस्ती की बढ़ती तमन्ना' (15 फरवरी) वाजिब लगी. वास्तव में हर शख्स को चुस्त-दुरुस्त रहना भाता है. पर जो तमन्ना आपने उजागर की है वह तो उच्चवर्गीय लोगों की लगती है. मध्यमवर्गीय और निम्नवर्गीय लोग हेल्थ क्लबों, ट्रैक सूटों या स्वास्थ्य संबंधी खाद्यों और उपकरणों के शौक कैसे पाल सकते हैं? उनके लिए कोई दूसरे तरीके सुझाइए.

—महेंद्र पाल, नई दिल्ली

■ तंदुरुस्ती के लिए एक देशव्यापी अभियान छेड़ने की जरूरत है. लोगों की तंदुरुस्ती में ही देश की तंदुरुस्ती छिपी है. लेकिन अधिकांश लोगों को जब भरपेट खाना ही नहीं मिलता, वे इस दिशा में सोच कैसे सकते हैं?

—अरविंद कुमार, हाथरस (उ.प्र.)

■ पश्चिमी देशों से भारत में पहले पाश्चात्य संगीत, फिर डिस्को डांस और अब संगीत की धुनों पर व्यायाम लाया गया है. दूरदर्शन को चाहिए कि व्यायाम का अपने कार्यक्रम का समय दस मिनट से अधिक बढ़ाए ताकि लोगों में तंदुरुस्ती के प्रति नई चेतना जागृत हो.

—राकेश खुराना, सोनीपत (हरियाणा)

असली चेहरा

'सांच पर आंच' (15 फरवरी) पढ़ा. जब 'तमस' मात्र उपन्यास के रूप में था तब किसी ने इसका विरोध करने की जरूरत नहीं समझी मगर टीवी सीरियल के रूप में आते ही लोगों ने हो-हल्ला मचा दिया. दूरदर्शन के जरिये असंख्य लोगों पर ऐतिहासिक सचाई का प्रकट होना कुछ स्वार्थी लोगों को नागवार गुजरा. इसलिए 'तमस' देखते-देखते सांप्रदायिक हो गया.

—जया नर्गिस, भोपाल (म.प्र.)

■ दरअसल हम लोग अपना असली चेहरा शीशे में देखने को तैयार नहीं. तमस हमें हमारे देश और समाज का असली चेहरा दिखा रहा है.

—प्रमोद कुमार ओझा, गोरखपुर (उ.प्र.)

■ तमस का विरोध इतिहास का विरोध न होकर ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ने-मरोड़ने का विरोध है. इतिहास तो कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा अंग्रेजों का पिट्ठू बन स्वाधीनता आंदोलन के विरुद्ध काम करने का है. इंदिरा गांधी की इमरजेंसी का कम्युनिस्टों द्वारा समर्थन भी इतिहास है. क्या गोविंद निहलाणी अपने आकाओं के सच्चे इतिहास पर सीरियल बनाने को तैयार हैं?

—देवेंद्र सिंह चौहान, इलाहाबाद (उ.प्र.)

■ तमस के तम में भटकता इतिहास अधिक पुराना नहीं. 1942 से 1947 का स्वातंत्र्य इतिहास और 1962 का भारत-चीन युद्ध स्वयं ही साक्षी है कि कौन 'अभिशप्त' लोग 'तमस' के माध्यम से अपने तामसिक कृत्यों पर पानी फेरने का प्रयास कर रहे हैं.

—नरेंद्र 'भारती', नई दिल्ली

पहले क्यों नहीं

'नए खून की लाली' (15 फरवरी) पढ़कर आश्चर्य हुआ कि हमारी क्रिकेट चयन समिति ने इससे पूर्व श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ टेस्ट शृंखला में इन नए खिलाड़ियों को क्यों मौका नहीं दिया. अगर ऐसा हुआ होता तो हमें इतनी शर्मनाक हार नहीं खानी पड़ती.

—रवींद्र कुमार ठाकुर, सहरसा (बिहार)

विस्फोटक हालात

आवरण कथा 'नरक बनते नगर' (31 जनवरी) पढ़कर महसूस हुआ कि यकीनन देश के महानगरों में समस्याएं विस्फोटक स्तर तक पहुंच गई हैं. यह सब सरकार की गलत नीतियों के कारण हुआ है. शहरों में कस्बों और गांवों की अपेक्षा रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हैं. और फिर गांवों का यूरोपीय देशों की तरह पूर्ण विकास भी नहीं हुआ है. तभी गांववाले शहरों की ओर भागकर वहां हालात नाजुक बना रहे हैं.

—राव गजराज सिंह, नारनौल (हरियाणा)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

■ हम सभी शहर की चकाचौंध जिंदगी के आकर्षण में गांवों से शहरों की ओर खिंचे चले आते हैं परंतु यहां एक नाटकीय जिंदगी देखने को मिलती है. सरकार की सही योजना के अभाव में सारी नागरिक सेवाएं चरमरा गई हैं और ऊपर से जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप शहर की जिंदगी त्रासदीपूर्ण हो गई है. आवश्यकता है शहरों की समुचित दीर्घकालीन व्यवस्था की और गांवों में बेहतर रोजगार के अवसर मुहैया कराने की.

—चंद्र प्रकाश, गायघाट (पटना)

■ पूरे देश में फाइवस्टार की चमक-दमक हो रही है और हम 20वीं शताब्दी के आंसू भी नहीं पोंछ पा रहे हैं. आखिर कब हमारे नगर वास्तव में नगर कहलाने के काबिल होंगे. —रमेश चोपड़ा, रतलाम (म.प्र.)

■ एक तरफ कुत्तों को रहने के लिए भी एयरकंडीशन कमरे की व्यवस्था है और दूसरी ओर लोगों को खुली धरती पर भी सोने की जगह नहीं मिलती. कितनी असमानता है! और कैसी ये सरकार की नीति है? —नीरज खुरहान, मधेपुरा (बिहार)

■ शहरी समस्याएं तेजी से बढ़ती आबादी के कारण कम, सरकारी कुप्रशासन की वजह से अधिक हैं. ये समस्याएं बहुत बड़ी नहीं हैं. बस जरूरत है वैज्ञानिक और नियोजित योजनाएं बनाने तथा इन पर दृढ़ता के साथ अमल करने की.

—संजय श्रीवास्तव, इलाहाबाद (उ.प्र.)

परिवार को तरजीह

कसौटी स्तंभ के अंतर्गत 'हावी है परिवारवाद' पढ़ा. यह सही है कि वंश-परिवार को तरजीह दिए जाने की वजह से साधारण परिवारों से आए महत्वाकांक्षी, उचित व्यक्ति अपमानित होते हैं. पर इसके लिए हम लोग भी तो जिम्मेवार हैं. यह स्थिति हमारी कमजोर मानसिकता की वजह से उत्पन्न होती है. हमें ऐसे व्यक्ति का साथ किसी भी स्थिति में नहीं देना चाहिए जो सचमुच उपयुक्त नहीं है.

—संजय जैन, मुर्निजापुर (महा.)

■ समझ नहीं पाता कि कब तक इस देश की जनता एक ही परिवार के पूरे सदस्यों को क्रमशः या एक ही साथ राजसत्ता की कुर्सियों पर विराजमान करती रहेगी? अगर इसी तरह परिवारवाद और उत्तराधिकार का दौर चलता रहा तो लाल बहादुर सरीखा कोई देशभक्त प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा.

—दीपनारायण सिंह, खड़गपुर (प. बंगाल)

■ यदि किसी केंद्रीय मंत्री की पत्नी उपचुनाव लड़ती है तो इसमें दोष किसका है? चुनाव में खड़ा करने वालों का या चुनने वाली जनता का? परिवारवाद के संक्रामक रोग से छुटकारा दिलाने के लिए जनता को समझने और समझाने की आवश्यकता है.

—इंतिखाब जाफर, बंगलूर (कर्नाटक)

'दयालुता' काबिले तारीफ

'निर्जन टापू पर निश्चित पड़ाव' (31 जनवरी) पढ़कर अत्यंत क्षोभ हुआ. व्यस्त जीवन में आराम के कुछ दिन तर्कसंगत हो सकते हैं. पर जब भारत के छह हजार रुपए मासिक वेतनभोगी प्रधानमंत्री आराम के इन दिनों में न केवल परिवार और रिश्तेदारों के साथ बल्कि मित्रों के साथ विकसित राष्ट्राध्यक्षों की भांति फिजूलखर्ची करे तब यह कहां तक तर्कसंगत बैठता है?

—महेंद्र अवस्थी, कुलपहाड़ (उ.प्र.)

■ जो प्रधानमंत्री हर महीने एक-दो विदेश यात्राओं पर रहता हो उसके लिए देश में ही रहकर 10 दिनों तक पिकनिक मनाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है. समस्याएं दिन-प्रतिदिन उग्र रूप लेती जा रही हैं लेकिन इससे प्रधानमंत्री की पिकनिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला.

—एम.एम. प्रभाकर, भिलाई (म.प्र.)

■ राजीव गांधी की दयालुता काबिले तारीफ है कि उन्होंने भारतीय जनता के सूखे में सूख जाने और बाढ़ में बह जाने की व्यर्थ चिंता करने की बजाय डॉल्फिन को बचाना उत्तम समझा. उनकी उदारता को दाद देनी चाहिए कि वे देशवासियों को रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, रोजगार मांगने पर टीवी, सुपर कंप्यूटर तथा 21वीं सदी के सपने दिखा रहे हैं जबकि देश अभी तक 19वीं सदी के बैलगाड़ी युग में है.

—विलियम ईम्मानुएल, बेतिया (बिहार)

■ आलोचकों को समझ होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री भी हमारी तरह हाड़मांस के इंसान हैं. उनकी भी इच्छा है कि वह सामान्य व्यक्ति की तरह कुछ क्षण अपने परिवार व रिश्तेदारों के साथ बिताएं. यह हर जीवित प्राणी का प्राकृतिक स्वभाव है.

—नरेश कुमार फंगु, बई बैजनाथ (हि.प्र.)

शर्म से झुका सिर

'परंपरा की व्यथा कथा (31 जनवरी) पढ़कर एक बार तो पूरा शरीर ही जड़वत हो गया. भारत जैसे देश में जहां महिलाओं की इज्जत और मान-मर्यादा ही उनका आभूषण होती है, वहीं मध्य प्रदेश में बांछड़ा जाति में अमर्यादा के नग्न नाच को देखकर कौन भारत की प्राचीन संस्कृति पर और उपरोक्त कथन पर विश्वास कर सकता है. —हरीश भास्कर, नई दिल्ली

■ बांछड़ा जाति की महिलाओं के यौन शोषण को पढ़कर सिर शर्म से झुक जाता है. साथ ही इससे महिला कल्याण का राग अलापने वाली सरकार और महिला संगठनों के मुख से नकाब उतरता प्रतीत होता है जो महिला कल्याण के नाम पर अपनी-अपनी रोटी सेंकने में लगे हुए हैं.

—अशोक शेखावत, चुरु (राज.)

■ केवल प्रस्ताव पारित करने से कुरीति समाप्त नहीं होती. इसके लिए आवश्यकता है जन जागरण की और साथ में ऐसे लोगों के लिए कल्याण के कार्यक्रम तैयार करने की. ऐसे स्थानों के आसपास छोटे-छोटे धंधों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जिससे पेट की भूख मिटाने के लिए नारी को अपनी देह का व्यापार न करना पड़े.

—कन्हैया लाल व्यास, महू (म.प्र.)

■ केवल परंपरा के नाम पर ऐसी मान्यता को मानना न केवल बांछड़ों बल्कि सारे भारत पर कलंक है. इस नासूर को जितना जल्दी हो खत्म किया जाए. ऐसे रिवाजों को रोकने के लिए सामाजिक चेतना जरूरी है.

—पवन दत्ता, रादौर (हरियाणा)

महंगा खामियाजा

'जल्दबाजी का महंगा खामियाजा' (31 जनवरी) पढ़कर एक बार तो रूह ही कांप जाती है. विश्व में महाशक्ति के रूप में पहचानी जाने वाली भारतीय सेना की ऐसी दुर्दशा देखकर सहसा विश्वास नहीं होता. भारतीय सेना को विजय तो मिलनी ही थी परंतु इसके लिए हमें कितनी क्षति उठानी पड़ी, यही हमारी हार-जीत का सही मापदंड था. और इस तर्कानुसार हम कतई सफल नहीं रहे हैं. —मंजु गर्ग, नई दिल्ली

■ लोकप्रियता की गरज से राजीव गांधी द्वारा किया गया समझौता देश के लिए

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

काफी महंगा साबित हुआ. बेचारे शांति सेना के बहादुर जवानों को एक ऐसी लड़ाई में अपना खून बहाना पड़ रहा है जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी.

—तारकेश कुमार ओझा, खड़गपुर (प. बंगाल)

■ जल्दबाजी का महंगा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है भारत मां के बीर सपूतों को और वाहवाही मिल रही है स्वार्थी राजनेताओं को. एक तो देश में शताब्दी का भयंकर सूखा और ऊपर से थोपा गया शताब्दी का सबसे भयंकर अनावश्यक भार. क्या इसे भारतीय जनता वहन कर सकेगी?

—शिव प्रकाश ओझा, सूरतगढ़ (राज.)

■ हमारे शासक लंका के मुक्ति चीतों को निरा बेवकूफ समझ बैठे थे. वे यह भूल गए कि अपने घर में तो 'गधा' भी 'शेर' होता है. दुश्मन के घर में बिना किसी सुरक्षा योजना के शांति सेना को क्या इस आशय से भेजा गया था कि वह अपने घर में कुछ तो मेहमाननबाजी का ख्याल करेगा. समझ नहीं आता राजीव और कब तक जाफना में सोने की लंका तलाशते रहेंगे?

—कु. कल्पना धोपे, दिल्ली

दिल कौन जीता?

'दिल जीतने की लड़ाई' (31 जनवरी) पढ़कर लगा कि वी.पी. सिंह अपने मकसद में सफल होने जा रहे हैं. उनको इतनी लोकप्रियता सिर्फ उनकी 'सुपर क्लीन' छवि के कारण ही मिल रही है. इंका एक बाजारू औरत की तरह व्यवहार कर रही है, सिर्फ वी.पी. सिंह को बदनाम करने के लिए. लेकिन स्वयं जनता की नजरों में गिर रही है. और वह दिन दूर नहीं जब वह समाज द्वारा बहिष्कृत कर दी जाएगी.

—नवीन कुमार वनरोपण, हजारी बाग (बिहार)

सराहनीय कार्य

'अनुकरणीय निर्णय' (31 जनवरी) पढ़ा. महाराष्ट्र सरकार ने गर्भजल परीक्षण पर रोक लगाकर सराहनीय कार्य किया है. अब उन डॉक्टरों का व्यापार नहीं चलेगा जो इश्तहारों में लिखते हैं कि कल 50 हजार खर्च करने से अच्छा है आज पांच सौ खर्च किए जाएं. स्त्रियों का हमारे समाज में कितना सम्मान है, इसका यह प्रमाण है. अन्य राज्यों सरकारों को भी चाहिए कि वे इस प्रकार के कदम उठाएं

—द्वारिका प्रसाद, डिब्रूगढ़ (असम)

चालाकी भरी बातें

'दरक रहा मजबूत किला' (31 जनवरी) में कर्नाटक के मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े ने बातचीत में बहुत चालाकी भरी बातें की हैं. पर अपनी बदरंग शक्ल दिखाने वाले आइने को चालाकी से दूसरी तरफ मोड़ देने से स्वयं की शक्ल उजली नहीं हो जाती, यह बात हेगड़े को समझ लेनी चाहिए. —मनमोहन द्विवेदी, उज्जैन (म.प्र.)

उनके लाडले

'गद्दी बचाने की तिकड़म' (31 जनवरी) पढ़कर लगा कि सचमुच कोई दुबे की 1000 दिन पुरानी कुर्सी छीनने वाला है. दुबे अब तक के किसी भी राज्य के अधिकतम निकम्मे मुख्यमंत्री से अधिक निकम्मे हैं तो जगन्नाथ मिश्र किसी भी राज्य के अधिकतम भ्रष्ट मुख्यमंत्री से अधिक भ्रष्ट.

—प्रमोद कुमार सिंह, रमपुरवा (बिहार)

यदि आपका जन्म १९६३ से पहले हुआ है तो इस विज्ञापन को ध्यान से पढ़िए

२५ साल से अधिक उम्र वाले १० में से ९ लोगों के बाल झड़ रहे हैं....लेकिन उन्हें इसका पता नहीं!

क्या आप उन ९ लोगों में से एक हैं? तब तो आज ही यह परीक्षण कीजिए

अपने बालों को ज़ोरों से कंघी कीजिए. अगर कंघी पर बाल उतर आएं तो समझ लीजिए आपके बाल झड़ रहे हैं.

इसका हल है — प्योर सिल्विक्रिन

बालों के झड़ने का कारण है — ज़रूरी अमिनो एसिड्स की कमी — जो आपके बालों की कुदरती खुराक है. केवल प्योर सिल्विक्रिन में ही वैज्ञानिक अनुसंधान से बना वह फार्मूला है जो इस कमी को पूरा करता है.

इसके कारण है :

१. प्योर सिल्विक्रिन १७ अमिनो एसिड्स का अनोखा मिश्रण है — आपके बालों की कुदरती खुराक.

२. नोबेल पुरस्कार विजेता अनुसंधान तकनीक यह प्रमाणित करती है कि प्योर सिल्विक्रिन बालों की जड़ों तक बहुत जल्दी पहुँचता है, बालों में कुदरती खुराक की कमी पूरी करता है और बालों को फिर से स्वस्थ बनाता है.

उत्तम परिणाम के लिए प्योर सिल्विक्रिन को सर की त्वचा पर तब तक प्रतिदिन दो बार मलिए जब तक आपके बालों का स्वास्थ्य सामान्य नहीं हो जाता.

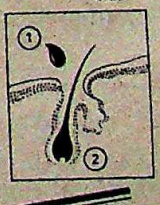

प्योर सिल्विक्रिन असरदार है — नोबेल पुरस्कार विजेता अनुसंधान तकनीक का प्रमाण.

प्योर सिल्विक्रिन

OBM/571/HIN

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

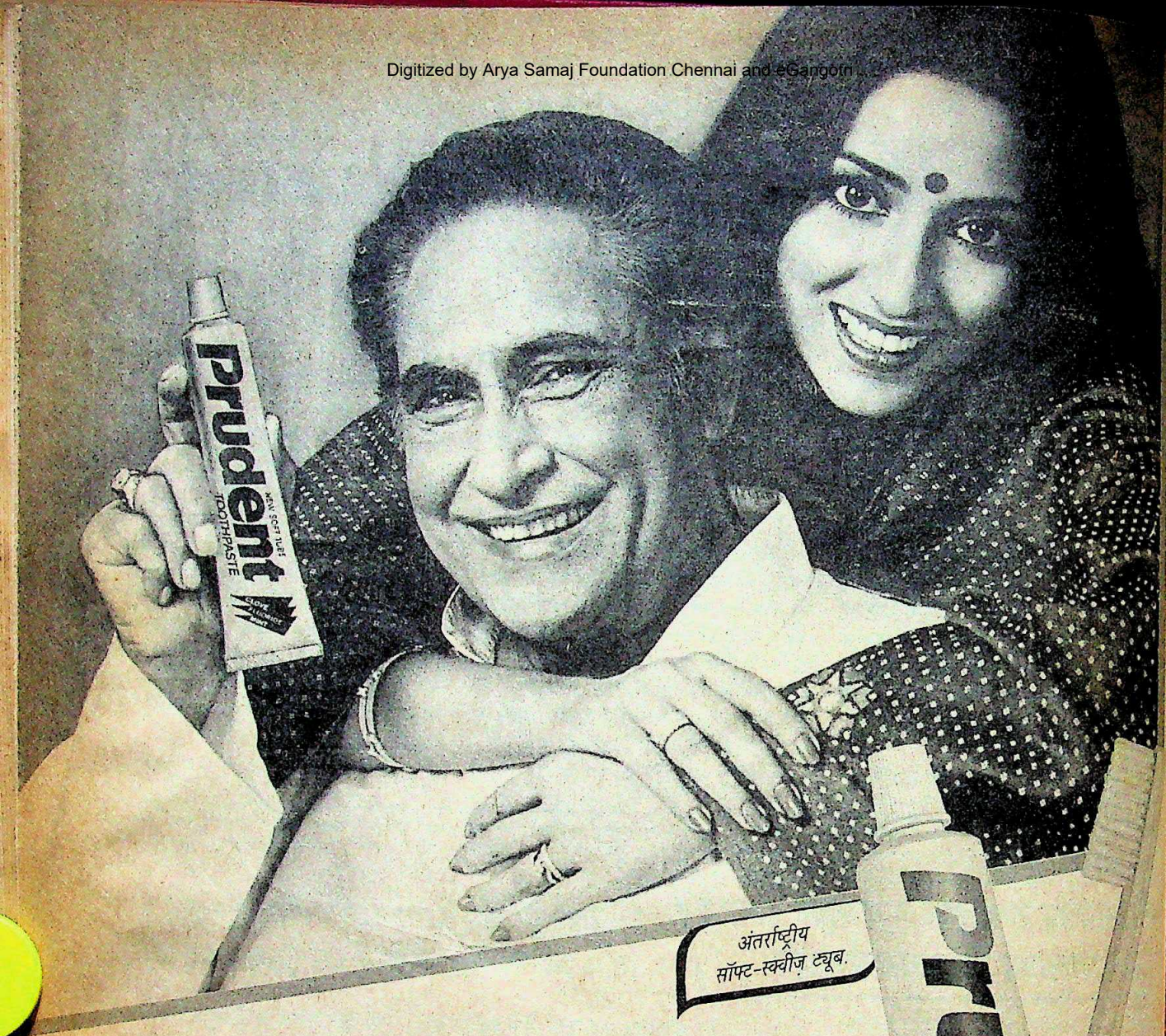

'३ कमाल वाला टूथपेस्ट क्यों हमने भी अपनाया"

"मानिए या ना मानिए, पर मैंने तो सचमुच अपना टूथपेस्ट बदल डाला है! अब मैंने अपनाया है **लौंग, फ्लोराइड** और **मिन्ट** के ३ कमाल वाला प्रूडेन्ट. है मेल इतना अच्छा, मानों दांतों का साथी सबसे सच्चा!
अनुराधा ने एक और खूबी पायी – प्रूडेन्ट की सॉफ्ट-स्क्वीज़ ट्यूब! सदा रहे साफ-सुथरी. ऐसी खूबी और किसी टूथपेस्ट में कहां है!"

मुफ्त! दांतों की देखभाल के लिए रंगीन पुस्तिका. सीमित संख्या में.
लिखिए : पारले प्रॉडक्ट्स प्रा. लि., निर्लोन हाउस, २५४-बी, डॉ. ए.बी. रोड, बम्बई ४०० ०२५.

प्रूडेन्ट में हैं कमाल ३, दांतों के लिए बेहतरीन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

पारले

इंडिया टुडे
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कसौटी

यों ही नहीं हैं किसान नाराज

करीब दस वर्षों से किसान इस आंधी के संकेत दे रहे थे. मेरठ में किसानों ने पिछले पखवाड़े विशाल संख्या में जिस तरह धरना शुरू किया और इसे कई दिनों तक जारी रखकर जिस ताकत और एकता का प्रदर्शन किया वह कुल मिलाकर उनके भीतर घुमड़ रहे गुस्से का ताजा इजहार ही माना जा सकता है. सरकार का अब तक का जो रवैया रहा है उसमें समस्या या संघर्ष के मूल बिंदुओं को समझने की कोशिश नहीं दिखती है उसकी तरफ से. किसानों का असंतोष थमता नहीं नजर आ रहा है. इसलिए अगर मेरठ जैसा हाल और जगहों पर न हो, कानून-व्यवस्था को भारी खतरा न हो जाए इससे पहले साफ नजरिये से काम करने की जरूरत है.

लेकिन मुसीबत यह है कि किसानों के सोच और सरकारी आंकड़ों के अनुसार अर्थव्यवस्था की स्थिति में मौलिक भेद है. किसान अगर सूखे वाले साल में बिजली के बिल को बोझ मानते हैं तो सरकार उन्हें पहले से ही कम दरों पर बिजली दिए जाने की बात याद कराती है. किसान अगर पैदावार की ज्यादा कीमत मांगते हैं तो सरकार इस तथ्य का हवाला देती है कि भारतीय किसानों को दुनिया भर के किसानों के मुकाबले कहीं ज्यादा कीमत मिलती है. और किसान अगर कर्जों को माफ करने की बात करते हैं तो सरकार इस पर बैंकों के साथ ज्यादती का जिक्र करने लगती है.

रेखाचित्र: अजीत नाइनन

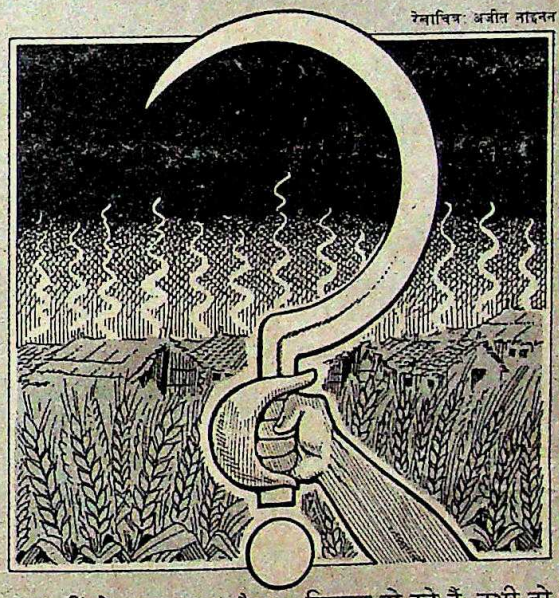

सरकार के नजरिये से कृषक वर्ग ही ऐसा अकेला समुदाय है जिसे आयकर नहीं देना पड़ता. और कृषि उपजों की कीमत कृषि लागत व मूल्य आयोग करता है. इसके नाम और इसकी कार्यशर्तों में किसानों की मांगों के अनुरूप परिवर्तन कुछ वर्षों पहले कर दिया गया था. और यही नहीं, कृषि क्षेत्र को अब कुल मिलाकर 5,000 करोड़ रुपए के आसपास रियायतें दी जा रही हैं. सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी निवेश से अगर पर्याप्त मुनाफा नहीं हो रहा (खासकर राज्यों में) तो इसके पीछे कुछ कारण यह भी रहा है कि राज्य बिजली बोर्डों को किसानों को दी जाने वाली बिजली में काफी रियायतें देनी पड़ती हैं. और कई राज्यों में सिंचाई की दरें इतनी कम हैं कि शुरुआती लागत तो दूर, सिंचाई व्यवस्था को बनाए रखने का खर्च भी नहीं पूरा पड़ता. और बैंकों से उन्हें कर्ज भी कम ब्याज दरों पर दिया जाता है.

महेंद्र सिंह टिकैत के भारतीय किसान यूनियन और शरद जोशी के शेतकरी संघटना के आलोचक यह भी आरोप लगाते हैं कि वे तो बस कुलक वर्ग के ही प्रवक्ता हैं. शायद यह सच भी है. मसलन गुजरात में भारतीय किसान समिति की एक मांग यह भी थी कि न्यूनतम खेतिहर मजदूरी समाप्त की जाए. और कई अर्थशास्त्रियों ने भी कहा है कि कृषि पैदावार की ऊंची कीमतों की मांग से कुल मिलाकर अमीर किसानों को ही फायदा होगा.

बहरहाल, सरकार और आर्थिक पंडितों की राय जो भी हो, किसानों के असंतोष का शमन तो करना ही होगा. एक लाख से ज्यादा किसान अगर दो हफ्ते तक मेरठ में धरने पर बैठे रहे तो उनके मन में किसी अन्याय के कारण असंतोष तो उबल ही रहा होगा. या फिर गुजरात के उनके शांतिप्रिय साथी बसें जलाने पर या महाराष्ट्र में सड़क और रेल यातायात ठप करने पर यों ही उतारू नहीं होते. गांवों में आम धारणा यही है कि किसानों के साथ ज्यादती होती रही है. और यह धारणा निराधार भी नहीं है.

कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली रियायतों को ही लें. इनका फायदा किसानों को उतना नहीं मिलता जितना शहरी उपभोक्ताओं को. जैसे उन्हें चीनी खुली बाजार दर से थोड़ी कम कीमत पर ही मिल जाती है. खेती की लागत का हिसाब करते हुए अगर बिजली, पानी और खाद आदि पर दी जा रही रियायतों को शामिल करें तो अंततः यही निष्कर्ष आएगा कि इसका फायदा अप्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं को ही होता है.

कर्ज माफी की किसानों की मांग भी निराधार नहीं है. देश भर में कर्ज बकाये की स्थिति भयावह है इसके बावजूद उन लोगों को और कर्ज दिए जा रहे हैं जिन पर पहले से ही कर्ज बकाया है. ऐसे में कर्ज माफी की मांग स्वाभाविक ही है. किसानों का असंतोष कुछ हद तक इस कारण भी है कि दूसरे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर नहीं बढ़ रहे हैं और खेती पर दबाव बढ़ रहा है. किसानों के बेटे बेरोजगारी के शिकार हो रहे हैं. तभी तो टिकैत मांग रखते हैं कि किसानों के बेटों को नौकरियों में आरक्षण दिया जाए. और किसानों को यह तो एहसास है ही कि वेतनभोगी वर्ग के मुकाबले कहीं हाड़तोड़ मेहनत का उन्हें अपेक्षया कम ही मेहनताना मिलता है.

टिकैत और जोशी की मांगों को मानना जैसे शून्य से गुणा करने का खेल हो—किसानों को जो भी रियायत दी जाएगी वह ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं की कीमत पर होगी लेकिन जब कीमतें तेजी से बढ़ रही हों तो फिर मामला पेचीदा हो जाता है. लेकिन सरकार भारतीय खाद्य निगम सहित दूसरे बिचौलियों के मुनाफे पर अंकुश लगा करके खेती को और आसान बना सकती है जिससे लागत और पैदावार की कीमतें घटें.

किसानों का गुस्सा आज बहुत कुछ इस कारण भी है कि उन्हें बिजली आम तौर पर रातों में ही मिलती है, या बेहद जरूरत के समय पानी नहीं मिल पाता. इन छोटी-मोटी शिकायतों पर सरकार ने ध्यान दिया होता तो शायद टिकैत की किसान यूनियन वजूद में भी न आ पाती. छोटे-मोटे सरकारी कर्मचारी अगर किसानों के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते तो उनका भड़कना जायज ही माना जाएगा. लेकिन उनके असंतोष को शांत करना बहुत दुरूह भी नहीं है.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारिए

यह कूपन और
अपनी चहेती आवाज़ सुनिए:
बच्चे की खिलखिलाहट

हंसी-खुशी और मौज-मस्ती बच्चों के लिए उतनी ही ज़रुरी हैं जितने ज़रुरी हैं खाना-पीना और हवा. और डिस्नी टुडे लेकर आया है यही मस्ती... यही मज़े.
बस तो फिर यह कूपन भर दीजिए और हर एक को खुश कर दीजिए.

आकर्षक छूट का लाभ उठाईये.

कूपन निम्नलिखित पते पर भेजें:
लिविंग मीडिया इंडिया (प्रा.) लि.
सबस्क्रिपशन डिपार्टमेंट
थॉमसन प्रेस बिल्डिंग
पो.बॉ. न० 69, दिल्ली-मथुरा रोड
फ़रीदाबाद - 121 007 (फ़रीदाबाद)

मुझे अपने बच्चे के लिए सबस्क्रिपशन चाहिए. यह रहा मेरा ☐ सालानाः रु. 78/- ☐ छह महीने काः रु. 40/- हिन्दी प्रति के लिए सबस्क्रिपशन मैं भुगतान चैक/मनी आर्डर/डिमांड ड्राफ्ट नं. _____ द्वारा कर रहा हूँ. कृप्या प्रति निम्नलिखित नाम व पते पर भेजें:

नाम _____
उम्र _____ लिंग _____
डाक-पता _____
_____
_____
विद्यालय _____
माता-पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर _____

कृप्या भुगतान लिविंग मीडिया इंडिया (प्रा.) लि. के नाम पर बनाएं.

Walt Disney
डिस्नी टुडे
अब उपलब्ध हर पखवाड़े
हिन्दी और अंग्रेज़ी में

© 1987 THE WALT DISNEY CO., USA.

MILESTONES/DT/114 Hin a

मुधीर तैलंग, नवभारत टाइम्स

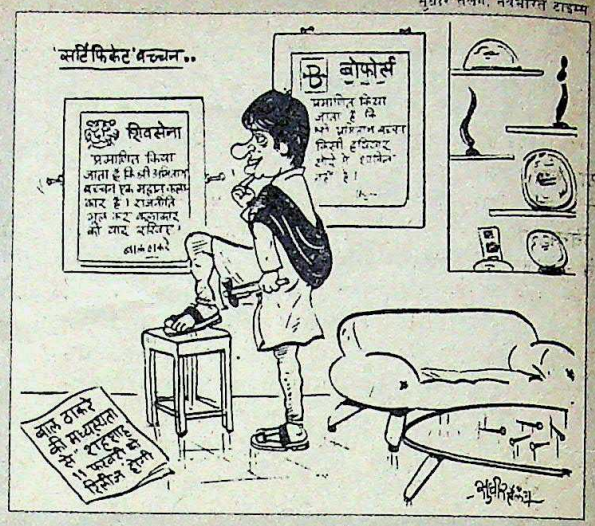

● मांग तो भिखारी करता है. किसानों को हक चाहिए.
■ **महेंद्र सिंह टिकैत,** *जनसत्ता*

● हमें कुछ नहीं करना. उनकी मर्जी है, बैठे रहें. आखिर कब तक बैठे रहेंगे किसान. दो-चार दिन बाद अपनेआप चले जाएंगे. ■ **बीर बहादुर सिंह,** *नवभारत टाइम्स*

● मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिन लोगों ने मेरे पति को भारत रत्न से सम्मानित किया वे मेरी सरकार को गिराने की कोशिश करेंगे. ■ **जानकी रामचंद्रन,** *इंडियन एक्सप्रेस*

● पैसे की लड़ाई में कांग्रेस का मुकाबला नहीं किया जा सकता.
■ **नृपेन चक्रवर्ती,** *रविवार*

● पंजाब का जो भी हल होगा वह गल (बातचीत) से होगा, गोली से नहीं.
■ **अर्जुन सिंह,** *दिनमान*

● वह (राजीव गांधी) तो धौल-धप्पे से चल रहे हैं. जितने दिनों चल सकेंगे, चलेंगे.
■ **विद्याचरण शुक्ल,** *माया*

● आज चोर को चोर कहने की किसी में हिम्मत नहीं है. किसी पर कीचड़ उछालना आम बात हो चली है. ■ **लहटन चौधरी** (कृषिमंत्री, बिहार), *हिंदुस्तान*

● मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हूं तो सिर्फ राजीव गांधी की मेहरबानी से.
■ **मोतीलाल वोरा,** *वही*

● यदि बंदा तय ही कर ले कि उसे तो भड़कना ही है तो पत्ते के खड़कने का बहाना काफी होता है. जब दिमाग ऐसे ठंस गए हों तो 'तमस' तो काफी है दहाड़ मार कर छाती पीटने के लिए. ■ **शरद जोशी** (व्यंग्य लेखक), *नवभारत टाइम्स*

● मेरी हस्तरेखाएं बताती हैं कि सिओल ओलंपिक के बाद मेरा विवाह निश्चित है. आखिर मैं कोई सारी उम्र थोड़े ही दौड़ती रहूंगी. ■ **पी.टी. उषा,** *नई दुनिया*

● स्कूल के जमाने से ही मुझे कप्तानी भाती रही है. ■ **दिलीप वेंगसरकर,** *स्पोर्ट्सस्टार*

● अंग प्रदर्शन से मुझे कोई एलर्जी नहीं है. ■ **मंदाकिनी,** *दैनिक जागरण*

● पूनम ढिल्लों से मेरी तुलना करके मेरा अपमान न करें... नीलम को मैं दूध पीती बच्ची कहती हूं... और रेखा की नकल की मुझे जरूरत नहीं. ■ **फराह,** *स्टारडस्ट*

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

राहत की सांस

● श्रीलंकाई राष्ट्रपति जूनियस रिचर्ड जयवर्द्धने की हाल की दिल्ली यात्रा के दौरान विदेश विभाग दम साधे बैठा रहा. वजह थी—'बूढ़ी लोमड़ी' कहे जाने वाले राष्ट्रपति की बिना आगा-पीछा देखे बेलगाम बोलते चले जाने की आदत. जयवर्द्धने एक बार शुरू हो जाएं तो

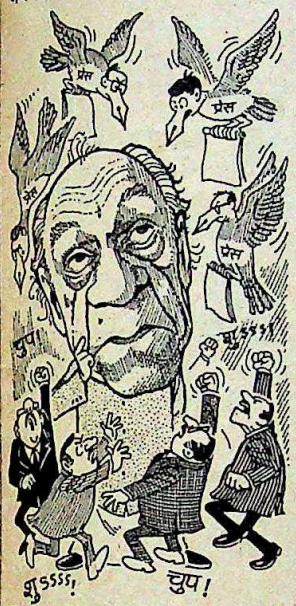

बिना किसी की नाराजगी या अपमान की परवाह किए अपनी रौ में लगातार बोलते ही चले जाते हैं. उन्हें यह भी ध्यान नहीं रहता कि वे कहीं राजनयिक मर्यादाओं का उल्लंघन तो नहीं कर रहे.

इसलिए किसी संभावित परेशानी से बचने के लिए विदेश विभाग ने एक नायाब तरीका ढूंढ़ निकाला. दिल्ली में भारतीय राजनयिकों ने जयवर्द्धने के साथ आए प्रतिनिधिमंडल के वरिष्ठ सदस्यों के कान में फूंका कि वे राष्ट्रपति को प्रेस से गज भर दूर ही रहने की सलाह दें ताकि राष्ट्रपति के मुंह से निकली किसी बात से बखेड़ा न उठ खड़ा हो. इस सलाह पर पूरी तरह अमल करते हुए प्रतिनिधिमंडल के सदस्य हर मौके पर प्रेस को चकमा देते रहे. विदेश विभाग के एक अंदरूनी सूत्र ने बताया कि विभाग को एक बात सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी. उन्हें खबरें मिली थीं कि जयवर्द्धने अखबारवालों से बातचीत के दौरान श्रीलंका से भारतीय शांति सेना की वापसी की मांग कर सकते हैं. भारत में उनके ऐसे बयान से माउथ ब्लॉक की खासी किरकिरी होती लेकिन सब कुछ चैन से निबट गया. और विदेश विभाग अब तक चैन की सांस ले रहा है.

प्रभु की माया

● भारी-भरकम कद-काठी के उर्वरक राज्यमंत्री आर. प्रभु और मंत्रिमंडल में उनके बॉस गुरदयाल सिंह ढिल्लों में पिछले कुछ महीनों से खटपट चल रही है. दो दिग्गजों के बीच इस लड़ाई का सबब है—मंत्रालय के तहत आने वाले सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्तियां और उनके सेवाकाल में वृद्धि.

कृषिमंत्री ढिल्लों अरसे से शिकायत करते आ रहे हैं कि प्रभु इन नियुक्तियों और सेवाकाल की वृद्धि के मामलों में उनकी राय नहीं लेते. पर प्रभु का कहना है कि उन्हें ढिल्लों से भी 'बड़े बॉस' राजीव गांधी का आशीर्वाद प्राप्त है. बताया जाता है कि कई बार वे सोनिया गांधी का भी नाम लेते हैं.

दोनों. की ताजा मुठभेड़ों का कारण बने सार्वजनिक क्षेत्र की उर्वरक इकाई के एक मुख्य अधिकारी. इन महोदय का कार्यकाल

कार्टून: अजीत नाइनन

समाप्त हो गया था. आदतन प्रभु ने ढिल्लों से पूछे बगैर इस अफसर के सेवाकाल में वृद्धि नहीं की और तुरंत उसका बोरिया-बिस्तर बंधवा दिया. इस मनमानी से ढिल्लों का रहा-सहा धैर्य भी खत्म हो गया. उन्होंने अपने कुछ सहयोगियों के सामने प्रभु के मनमानेपन की शिकायत तो की ही, राजीव गांधी को भी एक खर्रा लिख मारा कि वे प्रभु की खुराफातों पर अंकुश लगाएं और उन्हें बेवजह अपना वजन डालने से रोकें.

सुपरफोन पर भूल

● इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रति राजीव का मोह जगजाहिर है. हाल की स्वीडन यात्रा के दौरान वे

वहां इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने वाली नामी-गिरामी कंपनी एरिक्सन की फैक्टरी में गए थे. स्टॉकहोम के बाहरी इलाके में स्थित इस कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने उन्हें एक नवीनतम बेतार टेलीफोन दिखाया.

इस सुपरफोन की ढेर सारी खूबियां हैं. यह सही है कि सुपरफोन चांद की सैर नहीं करा सकता पर कई अजूबे अंजाम दे सकता है. कई खूबियों में एक यह भी है कि एक क्रोनर (स्वीडिश मुद्रा) डालकर आप दुनिया भर में कहीं से भी किसी भी देश में बात कर सकते हैं.

उस अधिकारी ने राजीव को सुझाव दिया कि वे चाहें तो दिल्ली में अपने संचारमंत्री से भी बात कर सकते हैं, और उन्होंने मंत्री का नंबर भी राजीव को थमा दिया. लेकिन स्वीडन की अजूबा इलेक्ट्रॉनिक तकनीक मानवीय गलती के सामने मात खा गई—राजीव को जो नंबर दिया गया, वह वास्तव में संचार सचिव डी.के. संगल के घर का था.

प्रधानमंत्री ने नंबर डायल किया और उधर संगल के घर का फोन घनघना उठा. फोन उठाया संगल की पत्नी ने. उन्होंने पूछा कि कौन बोल रहा है. रौबदार लहजे में उत्तर मिला, 'राजीव गांधी'. श्रीमती संगल ने इसे किसी की शरारत समझा और उसी लहजे में जवाब दिया कि संगल घर पर नहीं हैं, और फोन रख दिया. उधर स्वीडन में राजीव और स्वीडिश अधिकारियों ने इस भूल पर एकदम जोरदार ठहाका लगाया.

रिलायंस कप के बाद

● हाल ही में सोवियत संघ से भारत को टीयू-124 टोही विमान और परमाणु पनडुब्बी (जिसे नया नाम आइएनएस 'चक्र' दिया गया है) मिलने पर विरोध की जोरदार आवाज उठी है. पर आश्चर्य की बात यह है कि विरोध परंपरागत प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से नहीं बल्कि सुदूर आस्ट्रेलिया की ओर से हुआ है. ये पनडुब्बी और टोही विमान दूर तक मार कर सकते हैं.

कुछ आस्ट्रेलियाई पत्रकारों ने हाल में भारतीय विदेश विभाग के कुछ बड़े अधिकारियों को आ घेरा और बातचीत में उन्हें बताया कि भारत को मिले इन नए रूसी हथि-

यारों से आस्ट्रेलिया की सुरक्षा को खतरा हो सकता है. इस पर एक भारतीय कूटनयिक का जवाब था, "हां, हम आपकी मुखालफत का इरादा जरूर रखते हैं लेकिन किसी और क्षेत्र में नहीं, सिर्फ क्रिकेट के मैदान में. भारत में आकर रिलायंस कप झटक लेने का बाद आप हमसे और क्या उम्मीद रखते हैं."

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

घिस्सा चल गया

■ आम आदमी चोर के नाम से जैसा खौफ खाता है उसे देखते हुए यह कल्पना कर पाना भी मुश्किल लगता है कि किसी चोर के शिकार लोग पलक पांवड़े बिछाकर उसका स्वागत करें. पिछले दिनों दक्षिणी

सभी कार्टून: अनिल शर्मा

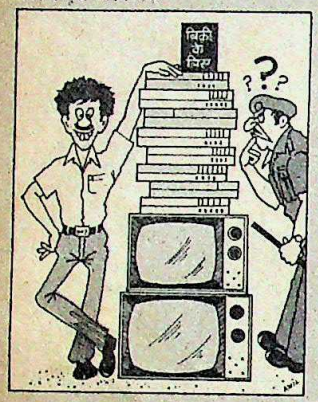

दिल्ली के एक चोर ने कुछ ऐसी ही उपलब्धि हासिल कर दिखाई—और वह भी एक घर या एक कॉलोनी में नहीं बल्कि कई घरों और कई कॉलोनियों में.

राजधानी की एक विज्ञापन एजेंसी में काम करने वाले इस 22 वर्षीय क्लर्क ने वीसीआर चुराने का नायाब तरीका ढूंढ़ निकाला. वह अक्सर मध्यमवर्गीय घरों में जाकर बताता कि उसके पास वीडियो तो है पर टीवी नहीं है. इसलिए अगर वे इजाजत दें तो अपना वीडियो और फिल्म लाकर वह उनके साथ फिल्म देख ले. तरकीब अक्सर काम कर जाती और लोग यह सोचकर उसे अपने यहां बुला लेते कि मुफ्त में फिल्म देखने को मिल जाएगी. फिल्म के दौरान उसे चाय नाश्ता भी दिया जाता. फिल्म समाप्त होने पर ये साहब वीडियो और फिल्म लेकर रवाना हो जाते. बेचारे घरवालों का संकट तब शुरू होता जब वीडियो वापस लेने के लिए आया दुकानदार उन्हें बताता कि वीडियो उनके नाम से किराए पर लिया गया था. चोर का धंधा अभी आगे भी चलता रहता लेकिन पिछले पखवाड़े एक सतर्क पुलिस वाले ने उस समय उसका खेल खत्म कर दिया जब वह नेहरू प्लेस की किसी दुकान में एक वीडियो बेचने की कोशिश कर रहा था.

हुनरमंद कैदी

■ हुनरमंद लोगों की एक खूबी होती है कि हालात भले ही कैसे हों वे हुनर का इस्तेमाल करने का कोई-न-कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं. पिछले पखवाड़े राजामुंदरी सेंट्रल जेल के एक कैदी के किस्से से भी यही साबित हुआ कि जेल की ऊंची दीवारें भी किसी व्यक्ति के हुनर को बांधे नहीं रख सकतीं.

देश के अन्य जेलों की तरह यहां भी अपराधियों को सुधारने के लिए उन्हें कुछ काम-धंधे सिखाने की व्यवस्था है. इस सिलसिले में वहां कपड़ा बुनने और रंगने का प्रशिक्षण देने के लिए एक केंद्र चलाया जाता है. पिछले दिनों जेल अधिकारियों ने जेल के बुनाई केंद्र के एक कोने में खुदाई करके नई धोतियों, साड़ियों, तौलियों, धागे और रंगों का एक जखीरा ढूंढ़ निकाला जिसकी कीमत 11 हजार रुपए थी. जांच करने पर पता चला कि यह करतूत वहां सजा काट रहे एक अपराधी की थी जो इसी केंद्र में काम करता था. बाद में पूछताछ करने पर पता चला कि वह केंद्र का सामान उड़ा लिया करता था और उसे एक गड्ढे में इस उम्मीद में दबा दिया करता था कि मौका मिलने पर माल जेल से बाहर भेजकर पैसा बना लेगा. कैदी की यह जखीरेबाजी अभी और आगे चलती लेकिन एक और कैदी ने उसका भंडाफोड़ कर दिया. जांच

के दौरान यह भी पता चला कि जब दूसरे कैदी को इस जखीरे की खबर मिली तब दोनों में यह तय हुआ कि वे इस माल को आपस में बांट लेंगे. लेकिन बंटवारे से पहले ही दोनों झगड़ बैठे.

रईसी का रुतबा

■ पुलिस को आए दिन तरह-तरह के अपराधियों के बारे में शिकायतें मिलती रहती हैं. लेकिन पिछले दिनों नागपुर की पुलिस एक ऐसे 'अपराधी' के बारे में मिलने वाली खबरों से हैरान थी

जो दिल खोलकर पैसे लुटाने में लगा हुआ था. पुलिस तक पहुंची एक खबर के अनुसार यह खूबसूरत नौजवान अपना नाम राजेश खन्ना बता रहा था. नाम का रुतबा कायम रखने के लिए उसने एक टैक्सी ड्राइवर का 25 रुपए का बिल अदा करते हुए उसे न केवल 225 रुपए बतौर 'टिप' दिए बल्कि इसके अलावा उसे एक सफारी सूट और पत्नी के लिए एक साड़ी भी थमा दी. स्थानीय रेड लाइट एरिया में मौजूद पुलिस के अंतरंग सूत्रों ने भी खबर भेजी कि ये सज्जन वेश्याओं के यहां मौज मस्ती कर रहे हैं और नकदी के अलावा साड़ियां भी लुटा रहे हैं.

हालांकि इनमें से कोई भी हरकत अपराध के घेरे में नहीं आती पर पुलिस जानने को उत्सुक थी कि ये सज्जन हैं कौन और लुटाने के लिए पैसा कहां से लाए हैं. पुलिस की खोज बहुत जल्दी पूरी हो गई क्योंकि एक ऑटोरिक्शा वाले के साथ हुई झड़प के सिलसिले में इन्हें एक स्थानीय थाने में लाकर पेश किया गया. वहां पूछताछ करने पर पता चला कि ड्राइवरों और वेश्याओं के यहां लुटने वाली कमाई दरअसल जमशेदपुर में रहने वाली इनकी बहन की थी जिसके घर से 35 हजार रुपए उड़ाकर ये सज्जन नागपुर में रईसी दिखाने पधारे थे.

'पूर्वज' की करतूत

■ यह किस्सा एक ऐसे बंदर का है जिसने पिछले दिनों न केवल इंदौर के नागरिकों की नाक में दम कर दिया बल्कि स्थानीय प्रशासन को भी नाकों चने चबवा दिए. स्थानीय पुलिस कंट्रोल रूम को खबर मिली कि ब्रह्मचारी कंपाउंड में एक बंदर घुस आया है जिसने लोगों के घरों में घुसकर और सामान उलट-पुलटकर आतंक फैला दिया है. जब तक पुलिस वहां पहुंचती तब तक बंदर ने घरों में हड़कंप मचाने के बाद स्थानीय मंदिर के प्रसाद पर भी हाथ साफ कर डाला. पता चला कि इससे पहले वह एक और इलाके में भी उत्पात मचा चुका था. वहां किसी ने उसे यह सोचकर भांग खिला दी थी कि वह शांत हो जाएगा. लेकिन भांग ने उलटा ही असर दिखाया. बंदर ने कृपा यह की कि भांग खिलाने वालों का इलाका छोड़ खुराफातों का केंद्र इस नए मुहल्ले को बना डाला.

पुलिस ने जब डंडे दिखाकर बंदर को धमकाने का प्रयास किया तो उसने एक सिपाही को बुरी तरह काट खाया. 'अपराधी' के इस रौद्र रूप से निबटने के लिए पुलिस अधिकारियों ने इस पर स्थानीय फायर ब्रिगेड वालों को बुला भेजा. फायर ब्रिगेड वालों ने बंदर को भगाने और उसके गुस्से को ठंडा करने के लिए पानी का इस्तेमाल

किया. पर इस तरकीब से बंदर को काबू करने में तो वे सफल नहीं हो पाए, हां उन नागरिकों का गुस्सा भड़काने में वे जरूर सफल रहे जिनका सामान पानी में खराब हो गया.

संकलन: विजय क्रांति

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

असुरक्षा का भाव प्रमुख

सुदूर पूर्वोत्तर में तेज चुनावी सरगर्मियों के साथ ही साथ पिछला पखवाड़ा जातीय असुरक्षा का अंधकार लाने वाला भी था. त्रिपुरा और मेघालय के चुनाव भले ही स्थानीय मुद्दों पर लड़े गए होंगे, पर इसने हमारे समय की एक बड़ी राजनैतिक त्रासदी—नेतृत्व की कमी को ही उजागर किया.

त्रिपुरा और मेघालय चुनाव ने कुछ अस्वाभाविक गठबंधनों को जन्म दिया है

पीटीआई

त्रिपुरा में एक दशक से सत्ता में जमे रहे वाममोर्चा के नेता नृपेन चक्रवर्ती को नकार तो दिया गया लेकिन यह बात साफ हो गई कि जनता के सामने कोई सही विकल्प नहीं है. इसने एक अस्वाभाविक गठजोड़ को भी जन्म दिया है. इंका में बंगालियों का प्रभुत्व है जबकि सत्ता में इसका सहयोगी दल पूरी तरह वनवासी समर्थक है.

यही जातीय विरोधाभास मेघालय में भी देखने को मिला. जहां राजनैतिक सवारों के लिए त्रिपुरा की ही तरह और भी अधिक असुरक्षा की हालत रही. शिलंग में मौजूदा जोड़तोड़ ने पूरे सत्र के लिए एक ऐसा अनिश्चय का मंच तैयार कर दिया है जहां छीना-झपटी जाने कब तक चलती रहेगी.

प्रमोद पुष्करणा

मेरठ के किसान आंदोलन ने जबरदस्त एकता और अदम्य उत्साह का प्रदर्शन किया है

लेकिन दोनों ही जगहों की मत पेटियां इस बात की सूचक थीं कि जातीयता एक प्रमुख राजनैतिक मुद्दा है. इस बात पर कतई विवाद नहीं था कि त्रिपुरा के चुनाव में जातीय असुरक्षा और केंद्र द्वारा अचानक सेना तैनात किए जाने से चुनावी संतुलन बदल गया. लेकिन प्रतिबंधित टीएनवी छापामारों द्वारा हाल में की गई हत्याओं ने एक मुद्दे को अखबार की सुर्खियों में जगह दे दी है. मेघालय में ढुलमुल सत्ता ने जनजातीय विभाजन को और गहराया है और जातीय मांगों की उपादेयता को जाहिर किया है.

गोरखालैंड समस्या पर बातचीत क्षुद्र राजनैतिक स्वार्थों का शिकार बन गई

दूसरी ओर एक और जातीय मुद्दा गोरखालैंड आंदोलन जानबूझकर अवसरों की अनदेखी करने का नाटक रचता रहा. नई दिल्ली में इस नाटक के प्रमुख खिलाड़ियों के बीच समझौते की स्थिति बनती लगी लेकिन राजनैतिक खेल भावना के कारण यह आशा शीघ्र ही जाती रही. केंद्र द्वारा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को दोषी ठहराना, ज्योति बसु द्वारा सुभाष घीसिंग को दोष देना और गोरखालैंड नेता द्वारा दोनों ही पर आरोप मढ़ने का सिलसिला आंदोलन की मांगों से भी लंबा हो चला है.

कुमार

तीन बहनों द्वारा की गई आत्महत्या ने भारतीय समाज की एक बड़ी बुराई का पर्दाफाश किया

इधर एक और समुदाय कुछ ज्यादा ही एकता और उत्साह के साथ अपनी मांगों को लेकर अड़ा रहा. चमत्कारी प्रभाव वाले महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में किसानों द्वारा मेरठ का घेराव जन-शक्ति और अदम्य उत्साह का एक बेजोड़ प्रदर्शन था. लंबे घेराव के कारण कई मौतें भी हुईं लेकिन इसने यह जता दिया कि भारतीय किसान यूनियन राज्य में एक बड़ी ताकत के रूप में उभरी है. किसानों और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच लड़ाई में तो अब समझौता न हो पाने की स्थिति आ गई है, लेकिन टिकैत और उनके समर्थक अब दिल्ली की ओर रुख किए हुए हैं.

बहरहाल नई दिल्ली अपने अलग धंधों में लगी है. सरकार की रंगरेलियों से और भी बढ़ता जा रहा राष्ट्रीय कर्ज चिंताजनक स्थिति तक जा पहुंचा है. लैटिन अमेरिकी देशों की ही तरह भारत सरकार कर्जों में इस तरह उलझ गई है कि कभी भी वह लड़खड़ा सकती है. और बजट आने के समय अब जो उपाय बचे हैं वे काफी कड़वे हैं.

दुर्भाग्य से एक बड़े संकट में कानपुर की तीन लड़कियों ने जो विकल्प चुना उसने पखवाड़े के मुख पर कालिख पोत दी. इन मौतों ने परिवार को गहरे दुख में लपेटने के साथ ही समाज की सबसे भयानक बुराई को नंगा कर दिया. दुख तो यह है कि इस दिल दहलाने वाली घटना के जिम्मेदार लोगों को कोई ग्लानि नहीं है.

—दिलीप बॉब

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

राजीव गांधी नया रूप, ब

राजीव गांधी को देश की बागडोर संभाले अभी कुछ महीने ही गुजरे थे कि 23 जून 1985 को एअर इंडिया का विमान कनिष्क दुर्घटनाग्रस्त हो गया. आयरलैंड के समुद्र पर उड़ते समय इसके परखचे उड़ गए. जब यह खबर पहुंची तो राजीव घर पर ही थे. उन्होंने दोपहर के खाने पर कुछ दोस्तों को बुला रखा था. तभी उनके टेलीफोन की घंटियां घनघनाने लगीं. पहले आयरलैंड के प्रधानमंत्री का फोन आया, फिर पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया उल हक ने फोन पर अफसोस जताया. अगली बार जब फोन की घंटी बजी तो दूसरी तरफ कैबिनेट सचिव थे. पायलट रह चुके राजीव के लिए यह त्रासदी अहम भी थी और निजी भी. पर वे जरा भी भावुक नहीं हुए और इस अचानक आ पड़ी जिम्मेदारी को बिना उत्तेजित हुए शांति से निबटाने में जुट गए. उन्होंने अपने भाषण का मसविदा तैयार किया, टेलीफोन पर बातें कीं और टेलीविजन देख रहे अपने बच्चों से बतियाने का समय भी निकाल लिया. मेहमानों ने सोचा कि राजीव शायद इस समय इस मेहमाननवाजी से छुट्टी पाना चाहेंगे इसलिए उन्होंने जाने की इजाजत चाही मगर राजीव ने रोक लिया.

तब वे 'मिस्टर क्लीन' ही नहीं 'मिस्टर कूल' (शांत) भी थे. तब उन्होंने अपने तौर-तरीके थोड़े अलग रखे थे. दबाव के बावजूद वे शांत थे, एक दिन एक काम को मजे से कर रहे थे. तब उनके भाषण बहुत जोशीले हुआ करते थे. यह उन दिनों की बात है जब राजीव ने बंबई के कांग्रेस शताब्दी समारोह के भाषण में पार्टी को सुधारने और सत्ता के दलालों को निकाल फेंकने का आह्वान किया था. यह उन दिनों की बात है जब '21वीं सदी' का नारा लफ्फाजी नहीं लगता था. यह उन दिनों की बात है जब राजीव ने प्रणव मुखर्जी और कमलापति त्रिपाठी जैसे दिग्गजों को एक हल्के से विरोध के कारण प्रमुख पदों से बाहर कर दिया था. वे अच्छी बातें करते थे, ये अच्छी लगती थीं और वे खुद भी अच्छे लगते थे.

1984 में राजीव गांधी

रघु राय

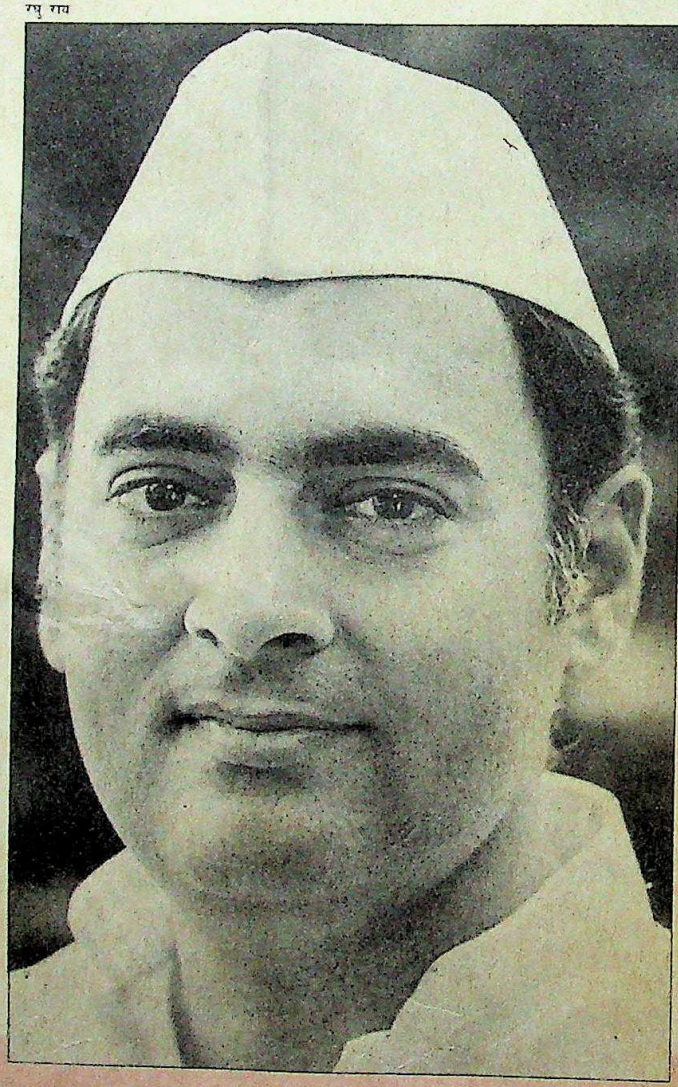

राजीव के जिगरी दोस्त कहते हैं कि तब से अब तक कुछ नहीं बदला. उनके एक स्कूली साथी के मुताबिक, "उनके नजरिये में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ. वे चीजों को आधुनिक व उदार बनाने और तुरत समाधान निकालने में पक्का विश्वास रखते हैं." अपने मकसद में नाकामयाब और कुछ दरकिनार हो गए राजीव के प्रति यह एक उदार मित्र का मूल्यांकन है.

राजीव से चिढ़ने वाले मानते हैं कि राजीव पर पिछले दो साल में जो संकट आए हैं उनमें उनका दंभी रूप सामने आया है. वे दुनिया के मंच पर अपनी हैसियत के बारे में आत्ममुग्ध थे. वे एक बहादुर नौजवान दिखना चाहते थे. पर वे ऐसे आदमी हैं

सत्ता में आने के बाद राजीव में जादुई करिश्मा कर दिखाने का माद्दा दिखाई देता था. वे उत्साह और चकाचौंध बिखेरते से मालूम होते थे. पर आज वे यथास्थिति के दलदल में धंस गए लगते हैं. एक के बाद एक संकटों के कारण वे अपनी राह से हटते जा रहे हैं...

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बदलते मिजाज

जिसका दिमाग तो तेजी से चलता है पर उलझे मसलों पर उसका बस नहीं चलता. पर सचाई इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच कहीं है. शायद संकटों के पहाड़ पार पाने के चक्कर में वे हालात के हाथों मारे गए हैं. एक संकट से निकलकर वे दूसरे संकट में फंसते जा रहे हैं. खुशवंत सिंह के शब्दों में 'दुनिया का यह सबसे खूबसूरत प्रधानमंत्री' अब थुलथुला होकर थोड़ा-थोड़ा अपने ममेरे भाई अरुण नेहरू की तरह दिखने लगा है. कुछ महीनों में उन पर तीन किलो चर्बी चढ़ गई है और ज्यादातर बाल तेजी से झड़ गए हैं. पहले उनकी चाल में एक कुदरती तेजी थी पर अब उन्हें इसकी कोशिश करनी पड़ती है. कभी उनके होंठ मुस्कराने के कारण ऊपर उठे होते थे, आज उनका मुंह लटका रहता है और परेशानियों में वे बुद्धू की तरह आंखें झपकाने लगते हैं.

आदमी जब भीतर से बदलता है तो ये बदलाव उसके चेहरे से झलकते हैं. राजीव को जानने वाले मानते हैं कि वे परेशान हैं, निराश हैं क्योंकि वे समय रहते वे सारे बदलाव नहीं ला सके जिनका उन्होंने वायदा किया था. उन्हें एहसास हो गया है कि उनके सलाहकारों ने प्रचार की जो भी तरकीबें निकालीं उनसे न तो उनकी छवि बदली और न ही तेजी से बदलाव का माहौल बना.

उन्हें यह एहसास भी हो गया है कि इंका की परंपरागत वोट बैंक की फसल काटने से ही जान बच सकती है. इसलिए बेहतर है कि अनुसूचित जातियों, मुसलमानों और औरतों की ही सुध ली जाए. हर समय कुछ-न-कुछ मांगते रहने वाले मध्यमवर्ग पर ध्यान देने से यही बेहतर है. कोई शक नहीं कि व्यवस्था ही राजीव पर हावी हो चुकी है. भारत के प्रधानमंत्री हार गए हैं, जबकि इसी दौरान थैचर और गोर्बाचेव कामयाब रहे हैं. दोनों ने अपने देश के कामकाज और राजनैतिक बहसों को बदल दिया है.

देश में इस समय कामकाज पुराने ढर्रे पर ही चलने लगा है—राजनैतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति और संयुक्त खुफिया समिति की नियमित बैठकें होती हैं. बाकी अधिकांश चीजें नौकरशाह और वह भी खास तौर पर प्रधानमंत्री सचिवालय के नौकरशाह संभालते हैं. राजीव के आते ही जो एक तेज बदलाव लग रहा था, उसी खौफनाक तेजी से पुरानी चीजें वापस आ गई हैं. अब राजीव गांधी व्यवस्था से नहीं लड़ रहे बल्कि व्यवस्था की मोर्चेबंदी में उनकी पार्टी और नौकरशाही के हित एक ही दुश्मन से जूझ रहे हैं.

पहले हर समस्या के बारे में राजीव का दीर्घकालिक नजरिया उनके व्यक्तित्व का बड़ा आकर्षक पहलू था. तब वे हर बात में कूटनीति के विरुद्ध थे. छोटे-छोटे राजनैतिक फायदों के मकसद से ही समझौता कर लेने जैसी कोई चीज नहीं थी

1988 में प्रधानमंत्री

प्रमोद पुष्करणा

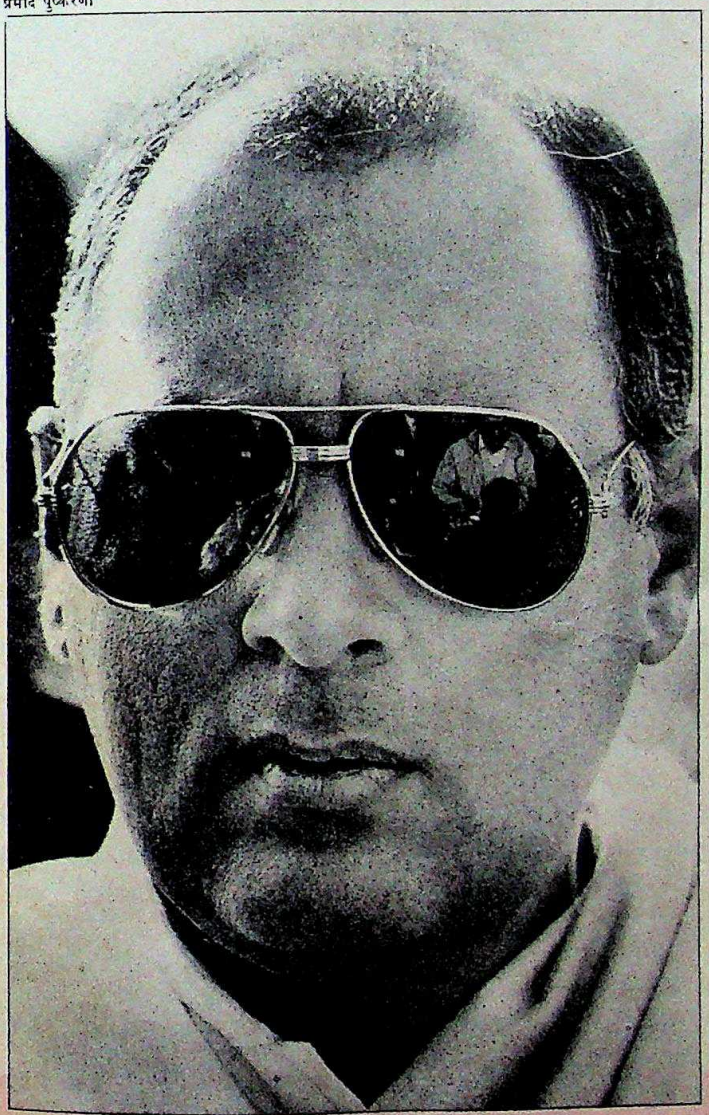

जब वे सत्तारूढ़ हुए तो उनके इर्दगिर्द एक ऐसा प्रभामंडल था कि व्यवस्था को उनसे खतरा लगता था. वे उसी पार्टी के साथ असुविधा अनुभव करते थे जिसने उन्हें कुर्सी पर बिठाया था. पर आज के राजीव गांधी की सार्वजनिक छवि, कठोर और निर्दयी राजनैतिक नेता की बन गई है.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रशांत पांजियार

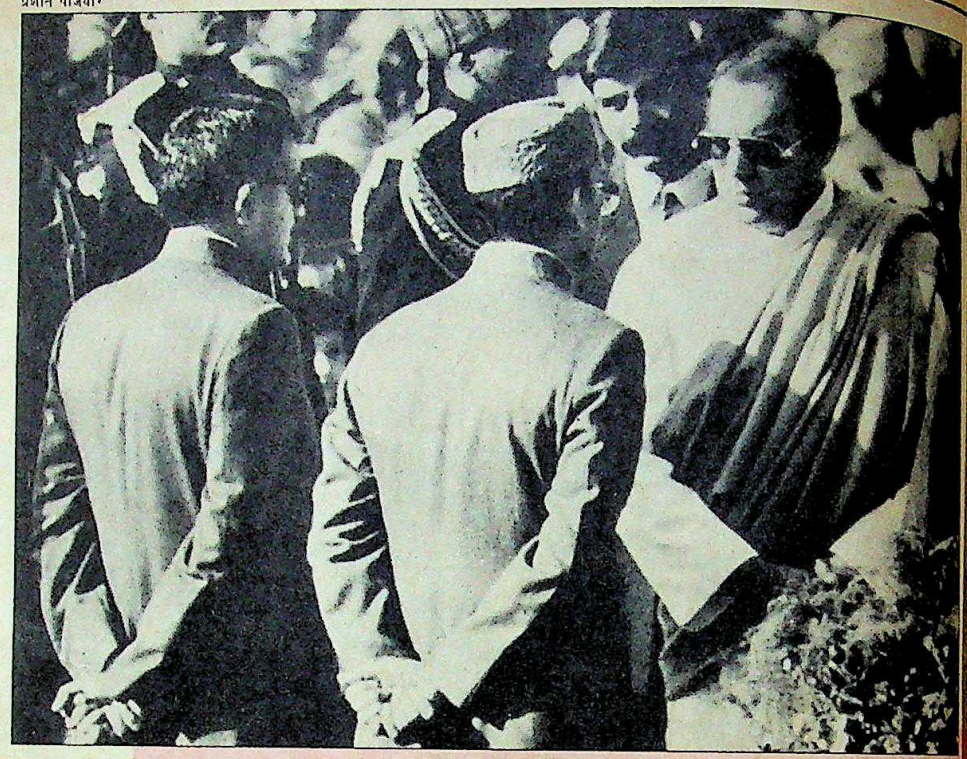

वी.पी. सिंह और अरुण सिंह के साथ राजीव

उनके पास. पर जब एक समुदाय के वोट बैंक को पक्का करने के लिए राजीव मुस्लिम महिला विधेयक ले आए तो उनकी यह छवि भी टूट गई. उन्होंने 'समाजवाद' की कसमें खाना शुरू कर दीं. असल में यह वी.पी. सिंह की चुनौती को उनका राजनैतिक जवाब था. यह उसी राजीव गांधी की बात है जो कभी कहते थे कि 'समाजवाद' के इस रोग का उन पर कोई असर नहीं होगा.

राजीव जिस भी मोर्चे पर बदलाव चाहते थे वहां उनकी टक्कर व्यवस्था से हुई और व्यवस्था जीत गई. राजनीति में वे अपनी पार्टी में नया उत्साह भरना चाहते थे. पर हुआ उलटा. उन्होंने पार्टी में सठियाए बुजुर्गों को ही प्रमुखता दी. नौकरशाहों में वे आइएएस अफसरों को हमेशा शक की निगाह से ही देखते थे पर आज वे ही छाए हुए हैं. उनका औद्योगिक और आर्थिक उदारवाद हवा में उड़ गया. विदेश नीति के लिए उनका वायदा था कि 'हम शांति और समझदारी से अच्छे पड़ोसी बनाएंगे.' पर उन्होंने पड़ोसियों पर धौंस जमाने की नीति ही चलाई.

राजीव ने सबसे बेहतर ढंग से काम तब किया जब अरुण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह और अरुण नेहरू उनके आसपास थे. उनकी एक टीम बनी हुई थी. वे एक तरह से सोचते थे और बदलाव चाहते थे....

और इन सब बदलावों से सबसे ज्यादा राजीव की अपनी छवि को नुकसान पहुंचा. एक समय था जब प्रधानमंत्री का सचिवालय और घर उनके सहायकों और राजनैतिक सहयोगियों की मुक्त चर्चाओं से गूंजता था कि कितनी जल्दी और किस सर्वाधिक सुगम रास्ते से 21वीं सदी में पहुंचा जा सकता है. अब यह बात नहीं चलती. यह अब न केवल उसे गढ़ने वाले व्यक्ति बल्कि पार्टी के लिए बहिष्कृत नारा बन गया है. राजीव ने न सिर्फ परंपरावादियों का चोला ओढ़ दिया है बल्कि उन्हीं की तरह का आचरण भी करने लगे हैं. एक समय पार्टी के चाटुकारों और नजरे इनायत चाहने वालों को तिरस्कार करने वाले राजीव अब मुलाकात करने आए मुख्यमंत्रियों को कई दिनों तक लटकाए रहने में आनंद पाते हैं.

राजीव ने अपने आपको अलग-थलग रखना शुरू कर दिया है. किसी भी मुद्दे पर वे एक खास व्यक्ति, राजनीतिक अथवा नौकरशाह की सलाह ही मानते हैं और इसी विषय पर उनसे चर्चा कर रहे सहयोगियों से इस सलाह का जिक्र तक नहीं करते. कभी-कभार वे सहयोगियों को नए विचार सुझाने के लिए प्रोत्साहित तो करते हैं लेकिन भूले-बिसरे ही उन्हें गंभीरतापूर्वक लिया जाता है अथवा क्रियान्वित किया जाता है. राजीव अस्पष्ट अथवा एकदम गुपचुप तौर पर दी गई सलाहों पर कार्रवाई कर देते हैं. कई बार तो यह भी होता है कि किसी फैसले पर अमल होने के घंटे पहले तक भी वे उसे लेकर अनिश्चित रहते हैं. यदि कोई व्यक्ति जोरदार ढंग से कोई दलील पेश करता है और राजीव उससे बेहतर नहीं जानते तब वे सीधे-सीधे उसके अनुसार चलने लगते हैं.''

पंजाब जैसे अहम राष्ट्रीय मसले पर केंद्र के पशोपेश से उनकी इस कार्यशैली का पता चलता है. वहां राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने से कुछ ही दिनों पहले राजीव के घनिष्ठ, पार्टी के एक महासचिव उनसे मिले और एक घंटे तक सारे मसलों की जानकारी दी. उन्होंने बरनाला सरकार को लगातार समर्थन देने की सलाह दी थी. राजीव राजी भी हो गए थे. कुछ ही दिनों बाद मंत्रिमंडल ने पंजाब मसले पर गौर करने के लिए बैठने का फैसला किया. संचारमंत्री अर्जुन सिंह ने उस शाम बरनाला को अनौपचारिक रूप से मंत्रिमंडल को स्थिति की जानकारी देने के लिए बुलाया. मुश्किल से आधा घंटे बाद ही गृहमंत्री बूटा सिंह ने बरनाला से बात की और कहा कि उन्हें अब दिल्ली आने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति शासन लगाना लगभग तय कर लिया है. एक घंटे बाद राजीव ने व्यक्तिगत रूप से बरनाला से बात की और उनसे कहा कि मंत्रिमंडल वैसे तो राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने पर चर्चा कर रहा है लेकिन वे और अर्जुन सिंह उनका समर्थन करेंगे. राजीव ने कहा कि यदि वे अपने सहयोगियों को मनाने में कामयाब नहीं हुए तो कुछ ही अरसे के लिए राष्ट्रपति शासन लगवाएंगे. यह एक अस्थायी व्यवस्था होगी और फिर बरनाला को ही वापस लाया जाएगा. पर राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद न सिर्फ उनका वायदा धरा-का-धरा रह गया बल्कि राज्य में अमन वापसी के लिए चल रही समानांतर कोशिशों को भी पलीता लग गया. ये कोशिशें

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

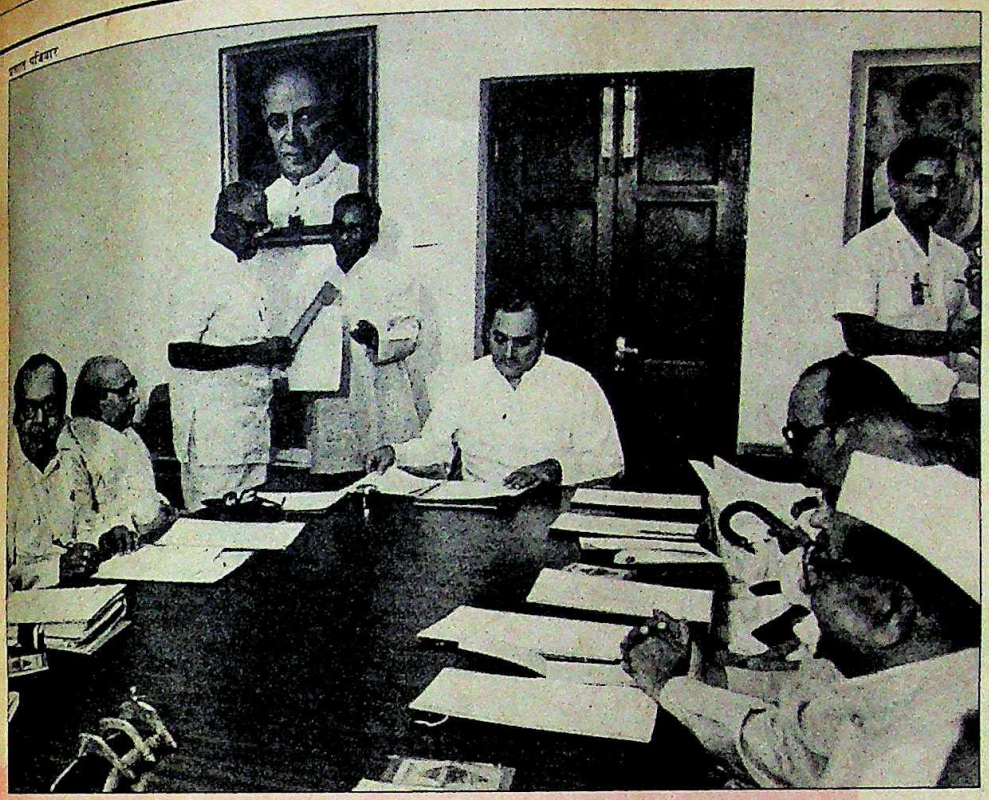

....पर उनकी कार्यशैली से घबराए तंत्र ने जवाबी हमला करके राजीव को अपने हिसाब से चलने को मजबूर कर दिया. राजीव ऊर्जा से भरी पार्टी चाहते थे पर उन्हें बुजुर्ग नेताओं का ही सहारा लेना पड़ा

और कोई नहीं बल्कि राजीव के भरोसेमंद दोस्त सतीश शर्मा ही कर रहे थे. उन्होंने दर्शन सिंह रागी के जरिये कुछ उग्रवादी गुटों से बातचीत चला रखी थी.

राजीव का दफ्तर अब इस कदर दरबारी राजनीति में उलझ गया है कि मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, प्रदेश इंका अध्यक्षों और अखिल भारतीय इंका महासचिवों को ज्यादा आजादी देने के उनके शुरुआती विचार का अब कोई वजूद ही नहीं रहा. राजीव का विचार था कि पदाधिकारियों को ज्यादा आजादी दे दिए जाने पर उनका दफ्तर सिर्फ तालमेल बिठाने और नीति बनाने का ही काम करेगा. उत्तर प्रदेश के एक इंका सांसद का कहना है, "राजीव जी अब फैसला करने से पहले हर बात जानना चाहते हैं. शायद दूसरों के फैसलों पर उन्हें भरोसा नहीं रहता या फिर वे यह बात पुख्ता कर लेना चाहते हैं कि सही फैसला ले लिया गया है." यह मानने के पर्याप्त कारण हैं कि राजीव अपने कार्यकाल के पहले वर्ष में जिस तरह की स्वतंत्र और वास्तविक सूचनाएं पाने के अभ्यस्त थे, अब नहीं रहे. सिर्फ अपने दफ्तर और इंका आलाकमान के ही भरोसे रहने के कारण अब वे बाकी स्रोतों से अलग-थलग पड़ गए हैं.

उनके एक सहयोगी याद करते हैं कि पश्चिम बंगाल और केरल के चुनावों के मौके पर उनकी एक टिप्पणी से वे कैसे हैरान रह गए थे. राजीव को पक्का भरोसा था कि इंका पश्चिम बंगाल में वामपंथियों का तख्ता पलट देगी और केरल में भी सरकार बनाएगी.

कभी-कभी तो उन्हें ताजा घटनाओं की भी खबर नहीं रहती. मिसाल के तौर पर जम्मू में लगातार चले बंद के कारण जब दो हफ्तों तक राज्य का जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया और इससे इंका की छवि बुरी तरह बिगड़ी तो एक वरिष्ठ सहयोगी ने राजीव को मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर दबाव डालने का सुझाव दिया. सहयोगी का कहना था कि फारूक से श्रीनगर को स्थायी राजधानी बनाने के विरोध को नाकारा करने के लिए कहा जाना चाहिए. राजीव की प्रतिक्रिया थी, "यानी आप कहना चाहते हैं कि जम्मू का आंदोलन अभी भी चल रहा है." उन्हें इतनी खबर भी नहीं थी.

कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में प्रधानमंत्री

राजीव जब सत्ता में आए तब वे साफ-सुथरी सरकार देने और विकेंद्रीकरण की जरूरत की बातें करते थे. तीन वर्षों बाद इसके ठीक उलटा हुआ—खुद राजीव का दफ्तर दर्जन भर से ज्यादा सलाहकारों और सचिव स्तर के आधा दर्जन अफसरों से भर गया जो प्रधानमंत्री के अधीन 20 विभागों का नियंत्रण करते हैं.

जनवरी 1985 में राजीव ने जब सचिवों और मंत्रियों से कहा था कि फाइलें उनके ही स्तर पर निबटा दी जाएं तब उनकी सबने मुक्त कंठ से प्रशंसा की थी. लेकिन अब यदि एक मंत्रालय एक उप-सचिव नियुक्त करना चाहता है अथवा एक बैंक एक नया निदेशक तो उसकी फाइल प्रधानमंत्री सचिवालय में पहुंचनी जरूरी है. एक वरिष्ठ सरकारी सचिव ने कहा, "प्रधानमंत्री सचिवालय कभी इस कदर शक्तिसंपन्न नहीं रहा जितना कि वह आजकल बन गया है."

राजीव के आधुनिक प्रबंधकीय नजरिये के कारण शहरी विकास और मानव संसाधन विकास, आंतरिक सुरक्षा और जल-संसाधन जैसे नए विभागों और मंत्रालयों का गठन हो गया. इन नए विभागों को, जैसा कि इनके बारे में राजीव का कहना है, कार्यक्रमों पर आनन-फानन में अमल करने की भावना के प्रति 'प्रतिबद्ध' होना चाहिए था. लेकिन ऐसे ही कामों के लिए प्रधानमंत्री के अधीन नए विभागों का गठन जारी रहने के कारण ये विभाग कुछ हद तक गैरजरूरी बन गए हैं. मसलन प्रधानमंत्री के ऊर्जा और आंतरिक सुरक्षा विभागों के सलाहकार मंत्रियों तक की बात नामंजूर कर सकते हैं. और हालांकि प्रधानमंत्री योजना आयोग की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं फिर भी उन्होंने आर्थिक मुद्दों पर सलाह देने के लिए सुखमय चक्रवर्ती के नेतृत्व में एक अलग पैनल बना रखा है.

प्रशासकीय मशीनरी की तरह ही प्रधानमंत्री के राजनैतिक सलाहकार भी दिग्भ्रमित हैं. राजीव ने केंद्र और राज्यों में स्थायित्व लाने का वायदा किया था. लेकिन अपने कार्यकाल के 39 महीनों के दौरान उन्होंने हर तीसरे महीने एक के हिसाब से 12 मुख्यमंत्रियों और इंका के 16 महासचिवों को

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बदला तथा 22 बार अपने मंत्रिमंडल में फेर-बदल किए, जिससे 60 सांसदों के दिन बने-बिगड़े. राजीव के आने के बाद प्रदेश इंका के भी छह अध्यक्ष बदल दिए गए. पार्टी में समय पर चुनाव कराने और चुने गए प्रतिनिधियों को पदाधिकारी नियुक्त करने की कसमें खाने वाला व्यक्ति ही आज किसी-न-किसी बहाने पार्टी चुनावों को लगातार टालता जा रहा है.

प्रधानमंत्री-राष्ट्रपति विवाद, सुरक्षा सौदों के घोटालों और विश्वनाथ प्रताप सिंह-अरुण नेहरू गठजोड़ की चुनौती के कारण जैसे ही पार्टी में अनिश्चितता और असुरक्षा की भावना गहराई राजीव की 'मिस्टर क्लीन' की छवि तेजी से धूमिल होने लगी. तब उन्हें लगा कि आजमाए हुए खेवनहारों यानी चौकन्नी नौकरशाही का सहारा लेना चाहिए. क्योंकि अब लड़ाई एक प्रत्यक्ष विपक्ष से थी, अपनी सलामती के लिए उन्हें अपनी माता के भरोसे वाले परंपरागत वोट बैंक को फिर से विश्वास में लेना पड़ा. अब उन्हें बूटा सिंह, जी.के. मूपनार, पी. शिवशंकर, सीताराम केसरी और कमलकांत तिवारी जैसों तक के सहारे की जरूरत थी. लेकिन उन्हें परंपरागत कांग्रेसी संस्कृति के अनुरूप बोलने, सोचने और व्यवहार करने की कीमत चुकानी पड़ी. इंका के एक पूर्व पदाधिकारी कहते हैं, "उन्हें लगा कि जिन पर उन्होंने भरोसा किया वही दगा दे गए. वे उन्हें सबक सिखाने की सोचने लगे. यह एक महत्वपूर्ण बदलाव था."

1987 के खत्म होते-होते राजीव की पूरी ऊर्जा और उनका ध्यान अपने विरोधियों से जूझने में ही लगने लगा. अब उनके पास अपने इर्द-गिर्द इकट्ठा हुए विचारकों, योजनाकारों और नवोन्वेषकों के लिए कोई वक्त नहीं बचा. ऑस्कर फर्नांडीस और गुलाम नबी आज़ाद जैसे युवाओं को महासचिव बनाया गया और केंद्रीय मंत्री जनार्दन पुजारी को कर्नाटक में विपक्षी सरकार के लिए मुश्किल खड़ा करने के लिए भेजा गया.

इस नई आक्रामकता से कुछ परिणाम निकलने लगे. 1987 का सूरज डूबने के पहले ही पार्टी ने नगालैंड में जीत हासिल कर ली. पुजारी और केंद्रीय व्यापारमंत्री प्रियरंजन दासमुंशी जैसे तेजतर्रार पार्टी पदाधिकारियों ने कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के विपक्षी मुख्यमंत्रियों के लिए जीना दूभर करके रख दिया है. केरल में स्थानीय निकायों और पंचायत चुनावों में 45 फीसदी सीटों पर जीत हासिल करके ए.के. एंथनी ने वहां एकाएक ही धारा मोड़ दी है.

त्रिपुरा में जीत और मेघालय में सरकार बना लेने समेत अभी तक की सारी उपलब्धियां तात्कालिक ही हैं. पार्टी और सरकार के भीतर अजीब तरह की उलझन बनी हुई है. सरकार के कैबिनेट मंत्री और राज्यमंत्री आपस में झगड़ रहे हैं और पार्टी के पदाधिकारी महत्वपूर्ण मुद्दों पर विरोधाभासी बयान जारी कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की नियुक्तियों के सवाल पर कानून और योजनामंत्री पी. शिवशंकर और उनके राज्यमंत्री हंसराज भारद्वाज में काफी मतभेद हैं. कृषि और रासायनिक खाद मंत्रालय में राज्यमंत्री आर. प्रभु अपने कैबिनेट मंत्री गुरदयाल सिंह ढिल्लों को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं. इन दोनों ही मामलों में सामंजस्य स्थापित करने में प्रधानमंत्री नाकाम रहे हैं. इसी तरह वे मध्य प्रदेश और गुजरात में पार्टी के अंदरूनी झगड़ों पर भी काबू पाने में नाकाम रहे हैं. सबसे बदतर तो यह है कि अब राजीव पार्टी में गुटबाजी को भी बढ़ावा देने लगे हैं. वरना पहले तो गुटबाजी में व्यस्त नेताओं को दरकिनार कर दिया गया था. राजस्थान में हरिदेव जोशी के स्थान पर शिवचरण माथुर को लाया गया. युवा इंका में गुरुदास कामथ को अनुशासनात्मक मामले लटके रहने के बावजूद आनंद शर्मा की जगह लाया गया.

हैदराबाद हवाई अड्डे पर अंजैया के साथ

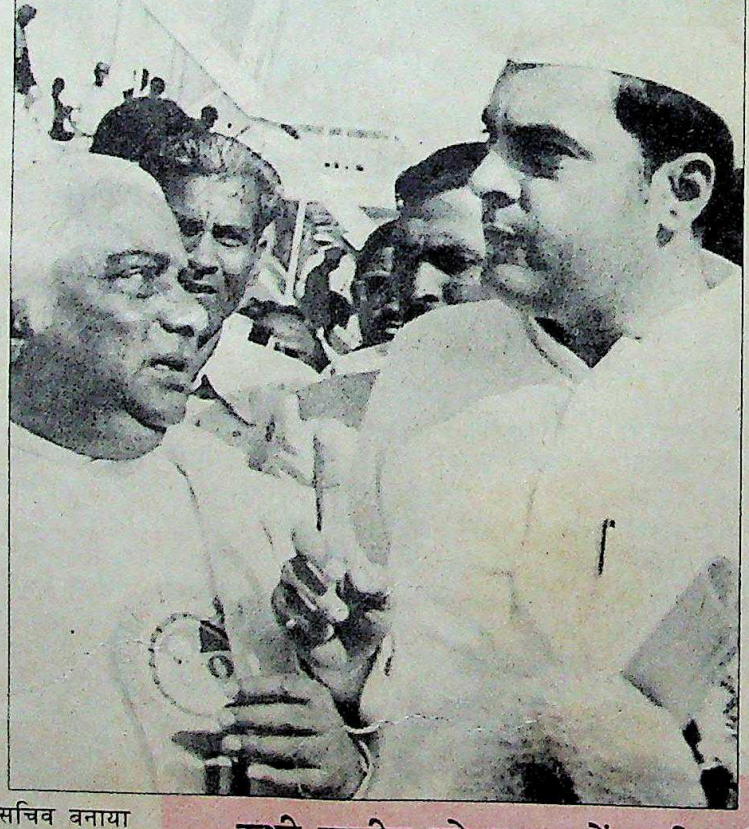

छह राज्यों में राज्यपालों के कार्यकाल खत्म हो रहे हैं इन स्थानों पर नियुक्ति के लिए सही आदमी ढूंढ़ने में भी वे नाकाम हैं. आधा दर्जन से अधिक हाईकोर्टों में अभी भी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ही काम चला रहे हैं. मंत्रियों के बीच झगड़ों के कारण 25 सरकारी निगम बिना मुख्य अधिकारी के ही चल रहे हैं. मारुती उद्योग चलाने वाले मुख्य अधिकारी लगभग पिछले चार महीने से करीब-करीब दिहाड़ी पर ही काम करते आ रहे हैं.

राजीव की शैली और प्रशासन में आए यह परिवर्तन अव्यवस्था, बीच-बीच में अचानक बदलाव, मनमाने फैसले और सही दिशा के अभाव की बेमिसाल कहानी कहते हैं. एक वरिष्ठ इंका मंत्री कहते हैं, "हमें

कभी राजीव को चापलूसों, दर्शन और नजरे-इनायत चाहने वालों का तिरस्कार करने वाला व्यक्ति माना जाता था. वे आधुनिक विचारों के दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति के रूप में राजनीति में आए थे....

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

एक नेता की जरूरत थी जो हमारा नेतृत्व कर सके. लेकिन हमारा नेता ही कइयों के नेतृत्व में चल रहा है." कर्नाटक के मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े कहते हैं, "मुझे अब पूरा यकीन हो गया है कि वे जटिल राष्ट्रीय मुद्दों और पेचीदा प्रशासनिक समस्याओं को ठीक तरह नहीं समझ पाते."

मजेदार बात तो यह है कि राजीव के करीबी लोगों का एकमत से मानना है कि उनके कार्यकाल का सबसे बेहतर समय वही था जब अरुण सिंह, अरुण नेहरू और विश्वनाथ प्रताप सिंह की टीम उनके साथ थी. यहां तक कि अरुण नेहरू का बड़ा-से-बड़ा दुश्मन भी मानता है उनकी कमी ही प्रधामंत्री की सबसे बड़ी क्षति है. जैसा कि राजीव के एक साथी ने कहा, "उनकी एक टीम थी. वे एक तरह से सोचते और काम करते थे. वे अफसरशाही और पूरी व्यवस्था से लड़ सकते थे. राजीव बदलाव चाहते थे और इस काम में वे लोग उनके नुमाइंदे थे. आज हालत यह है कि राजीव को ऐसे तमाम लोगों के साथ काम करना पड़ता है जो उन्हें ही नहीं सुहाते. विडंबना तो यह है कि एक व्यक्ति जो उन्हें सुहाता है वह भी विश्वनाथ प्रताप सिंह की ही आर्थिक धारा का है."

राजीव के समर्थक यह दावा नहीं करते कि वे राष्ट्र के लिए ईश्वर की देन है. उन्हें बुद्धिजीवी भी नहीं कहा जा सकता. उन्होंने खुद कभी भी गरीबी या फिर हिंदुस्तान की असली तस्वीर भी नहीं देखी. राजनीति में उनका प्रवेश एक स्वच्छ, पक्के इरादे और आधुनिक विचारों वाले ऐसे व्यक्ति के रूप में हुआ था, जिसके बारे में कल्पना की गई थी कि वह अफसरशाही और राजनीति के ढर्रे की नकेल एकदम से सीधी कर देगा.

और उन्होंने सत्ता में आते ही यही करना शुरू कर दिया. उनके पास काम करने वालों की टीम थी जो उनके कामों को हाथ में लेते और पूरी तत्परता से उन्हें पूरा करके उसकी सही रिपोर्ट देते. मगर इससे बंधे-बंधाए ढर्रे को खतरा पैदा हो गया.

राजीव के एक सलाहकार का कहना है, "मेरा ख्याल है कि असली समस्या उनकी पकड़ में आ गई थी. चाहे गांवों में खुदवाए गए कुओं के आंकड़ों की हो या रोगनिरोधक टीके लगाने का मामला, अधिकारी आपको लंबे-चौड़े आंकड़े तो दिखा देंगे लेकिन गांवों या व्यक्तियों के नाम कभी नहीं बताएंगे. क्योंकि वे मेजों पर बैठे रहकर ही झूठे आंकडे तैयार कर लेते हैं. इस तरह सरकारी पैसे को नीचे से लेकर ऊपर तक हजम किया जाता है."

राजीव के नजदीकी सूत्रों का कहना है कि उनकी सबसे बड़ी गलती थी अपने सबसे तेजतर्रार सहयोगी अरुण सिंह को रक्षा मंत्रालय में भेज देना. दरअसल यह सुझाव उनके अपने कार्यकाल के कुछ वरिष्ठ अफसरों का था जो प्रधानमंत्री को सीधे रिपोर्ट देने वाले संसदीय सचिवों से डरे हुए थे.

राजीव की सबसे बड़ी समस्या है ऐसे लोगों से घिरे रहना जो उनके विचारों में विश्वास नहीं रखते. वे औद्योगिक स्वतंत्रता चाहते हैं पर उद्योग मंत्रालय में फाइलें चलाने वाले वरिष्ठ अधिकारी ठीक विरोधी विचारधारा के हैं और इस कारण वे फाइलों को दाबे रहते हैं. फिर राजीव ऐसे लोगों से पीछा क्यों नहीं छुड़ा लेते? लेकिन यह इतना आसान नहीं है. प्रधानमंत्री के एक करीबी अधिकारी ने बताया, "कई लोगों को यह नहीं पता कि राजीव दबावों के प्रति संवेदनशील हैं और व्यवस्था के आगे झुक जाते हैं." वे न केवल व्यवस्था के आगे हथियार डाल देते हैं बल्कि लगता है कि वे खुद फैसला करने से भी डरते हैं. प्रधानमंत्री सचिवालय में एक मजाक काफी प्रचलित है. अगर राजीव को किसी बात के लिए राजी करना है तो आपको गोपी अरोड़ा के विचारों को मणिशंकर अय्यर के मुंह में डालना होगा. बस काम बन जाएगा.

राजीव की समस्या यह है कि उन्हें जनता की राय से काटकर रखा जा रहा है. उनके पास जो सूचनाएं पहुंचती भी हैं उनमें से अधिकांश राजनैतिक सहयोगियों और अधिकारियों की छलनी में से होकर ही पहुंच पाती हैं.

भोपाल में जिलाधीशों और प्रधानमंत्री के बीच हुई बैठक इसका एक उदाहरण है—जिसे तय करने में उनके सलाहकारों ने करीब छह महीने लगा दिए, जबकि राजीव ने पहले ही इस विचार को सिद्धांत रूप से तो मान ही लिया था.

इसी तरह आधिकारिक सलाहकारों ने प्रधानमंत्री की स्वतंत्र पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और अर्थशास्त्रियों के साथ होने

श्रीलंका से वापसी पर अगवानी

प्रमोद पुष्करणा

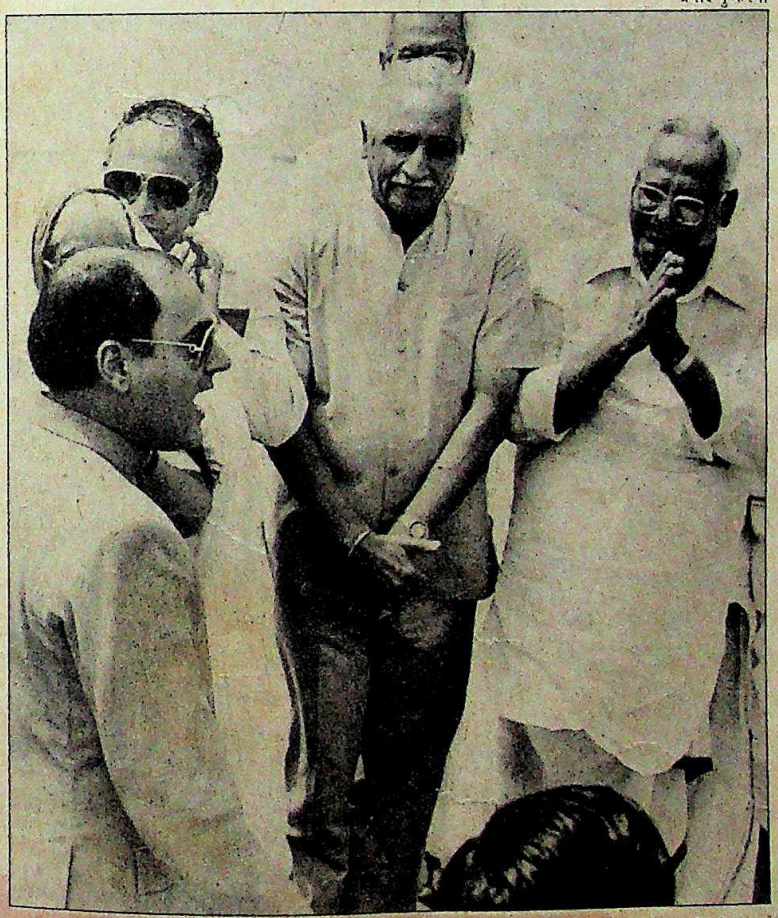

....लगता है अपने मंत्रियों को नीचा दिखाकर उन्हें बड़ा मजा आता है. दिल्ली दौरे पर आए मुख्यमंत्री बहुधा उनसे मिलने के इंतजार में अपने-अपने प्रदेशों के भवनों में कई-कई दिन सिकुड़े बैठे रहते हैं

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

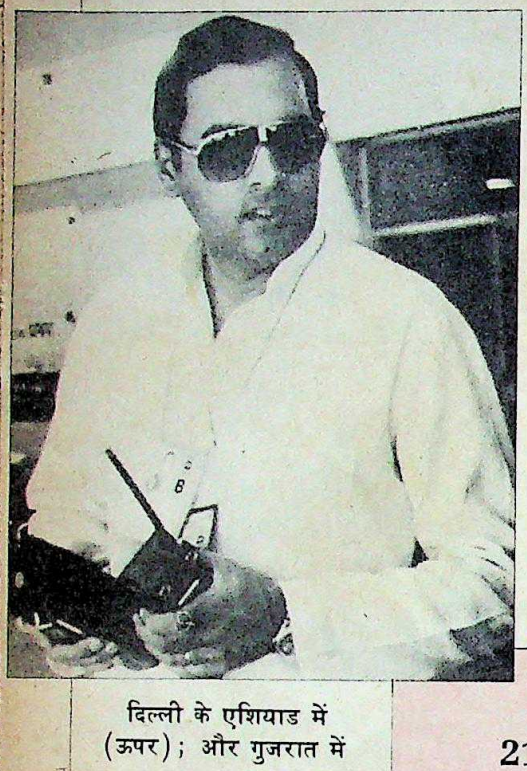

दिल्ली के एशियाड में (ऊपर); और गुजरात में

21वीं सदी का नारा अब लगभग अभिशप्त हो गया है. आज अल्पकालीन राजनैतिक फायदों के लिए इस मकसद की कुर्बानी दे दी गई है. अब राजीव ने कुछ तो परंपरावादियों का लबादा ओढ़ लिया है

वाली एक बैठक को आयोजित करने मे ही चार महीने से अधिक का समय लगा दिया. आखिरकार, प्रधानमंत्री के इन दरबानो ने बैठक रखी भी तो केवल आधे घंटे की. यह जुदा बात है कि बातचीत में राजीव को इतना मजा आया कि यह बैठक करीब तीन घंटे तक चलती रही. बैठक के बाद उन्होंने आदेश दिया कि ऐसी बैठकें नियमित तौर पर रखी जाएं. लेकिन उनके अधिकारियों ने बुझे मन से 'यस प्राइमिनिस्टर' तो कह दिया लेकिन इस बात की भी पक्की व्यवस्था कर दी कि भविष्य में ऐसी बैठकें न होने पाएं जिनमें प्रधानमंत्री को अफसरशाहों से मिलने वाली जानकारियों के अलावा और कोई सूचनाएं मिलती हों.

अधिकारियों के भितरघात का सबसे बड़ा उदाहरण एक टीवी कार्यक्रम था. जिन दिनों बोफोर्स का मामला जोरों पर था और राजीव राजनैतिक संकट में फंसे हुए थे, उस समय उनके कुछ सलाहकारों ने उन्हें दूरदर्शन पर दर्शकों के समक्ष अनौपचारिक रूप से अपनी सफाई पेश करने की सलाह दी. योजना यह थी कि राजीव उन मसलों पर लोगों से सीधे बातचीत करेंगे और उनके सवालों का जवाब देंगे. इस नजरिये से एक बैठक हुई जिसमें शिवशंकर, माखनलाल फोतेदार, गोपीकृष्ण अरोड़ा, सीताराम केसरी, अर्जुन सिंह, सैम पित्रोदा और मणिशंकर अय्यर ने दो दिन बाद अगले रविवार के लिए रिकार्डिंग का एक सत्र तय कर दिया. लेकिन कार्यालय में ही एक अधिकारी इसके खिलाफ था और जब टीवी के लोग रिकार्डिंग के लिए आए तो उन्हें बता दिया गया कि कार्यक्रम रद्द हो गया. इस योजना से उलट बोट क्लब पर एक आम सभा की गई जिसमें राजीव ने 'नानी याद दिला देंगे' वाला कुख्यात भाषण दिया.

और यही राजीव की विडंबना है. व्यवस्था में परिवर्तन लाने की उनकी इच्छा थी और इसके लिए उन्हें जनमत भी हासिल था. लेकिन वे यथास्थितिवाद के दलदल में फंस गए हैं. परिवर्तन में उनका साथ देने वाले या तो निकाल बाहर कर दिए गए या उन्हीं के विरोधी बन गए. राजीव विकेंद्रीकरण करना चाहते थे लेकिन व्यवस्था ने उनके इर्दगिर्द चाटुकारों की भीड़ जुटा दी जो प्रधानमंत्री सचिवालय की सहमति के बिना कुछ भी नहीं करते. और प्रधानमंत्री सचिवालय में अंदरूनी गुटबाजी मौजूद रही.

राजीव के सबसे खुशनुमा क्षण होते हैं जब वे अपने को अधिकारपूर्ण स्थिति में महसूस करते हैं. ऐसा ही एक अवसर था जब उन्होंने तत्कालीन विदेश सचिव ए.पी. वेंकटेश्वरन को सार्वजनिक तौर पर अपमानित किया था. दूसरी बार उन्होंने पूरे देश को ही ठेंगा दिखा दिया. वे अपने दोस्त अमिताभ बच्चन को भी लक्षद्वीप में छुट्टियां मनाने साथ ले गए. उनके एक सहयोगी ने कहा, "वे महसूस करते हैं कि प्रेस उन पर नाहक कीचड़ उछालता है. उनका रवैया यह रहता है कि "प्रेस कीचड़ उछालता है तो उछाले, मैं अपनी ही करूंगा.

राजीव में क्या बदलाव आए हैं, इस बारे में खुद उनका एक बयान ही सबसे सटीक है. नए साल के लिए फैसलों के बारे में 'इंडिया टुडे' के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, "समाचार माध्यमों को जरूरत से ज्यादा महत्व न देना." दो साल पहले यही राजीव समाचार माध्यमों के चहेते थे. देश और विदेश हर जगह उन्हें प्रेस के सामने आना अच्छा लगता था. और यही प्रेस है जिसने उनके राजनैतिक उद्देश्य, आधुनिकता के संदेश को दुनिया भर में पहुंचाया था. आज वह उद्देश्य भी गायब हो चुका है और ताल ठोंककर व्यवस्था से लड़ने निकले प्रधानमंत्री आज उसी व्यवस्था की गिरफ्त में आ गए हैं.

—इंद्रजीत बधवार और प्रभु चावला

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जनमत संग्रह

विकल्प की कमी

इंडिया टुडे ने मार्ग (मार्केटिंग ऐंड रिसर्च ग्रुप) को एक राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह करने का जिम्मा सौंपा. यह इस पत्रिका द्वारा छमाही जनमत संग्रह कराने की योजना की दूसरी कड़ी है (पहली 31 अगस्त 1987 के अंक में थी).

मार्ग के सर्वेक्षणकर्ता देश के 200 से अधिक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गए और 30 लोकसभा क्षेत्रों के 10,338 मतदाताओं से बातचीत की. इन चुनाव क्षेत्रों का चयन चुनाव भविष्यवाणी के विशेषज्ञ प्रणय राय ने वहां के चुनावी आंकड़ों के विश्लेषण के बाद किया. ऐसे चुनाव क्षेत्रों को चुना गया जो हर चुनाव में दूसरे क्षेत्रों की मानसिकता को प्रतिबिंबित करते हैं. कंप्यूटर ने इन 30 क्षेत्रों के मतदाताओं के मत को अलग-अलग करके देखा और इनके आधार पर उससे जुड़े क्षेत्र और फिर पूरे देश में इंका द्वारा जीते जाने वाली सीटों की संभावित संख्या का अनुमान लगाया गया.

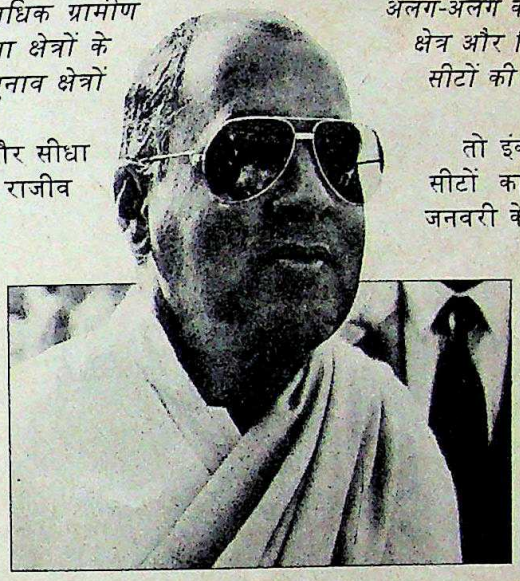

जनमत संग्रह का संदेश एकदम स्पष्ट और सीधा है. विपक्ष के बुरी तरह बंटे होने के कारण राजीव गांधी का विकल्प नहीं है.

इंडिया टुडे-मार्ग ने पिछले अगस्त में जब जनमत संग्रह किया था तब भी विकल्प नहीं था, अब भी नहीं है. बोफोर्स, फेयरफैक्स, आर्थिक मुश्किलों, श्रीलंका और पंजाब की मुश्किलों के लिए राजीव गांधी पर भले ही कितने आक्रमण हुए होंगे, पर चुनाव में आज भी वे और उनकी पार्टी इंका ही मतदाताओं की सर्वप्रथम पसंद बने हुए हैं.

जनमत संग्रह से पता चलता है कि अगर आज चुनाव हुए तो इंका 345 सीटें जीतेगी जो लोकसभा के 542 सीटों का 64 फीसदी हुआ. 20 जनवरी से 31 जनवरी के बीच हुए इस जनमत संग्रह से पता चलता है कि पिछले अगस्त के बाद राजीव गांधी की चुनावी संभावनाएं बेहतर हुई हैं. तब उनके 323 सीट जीतने का अनुमान था.

यह अनुमानित संख्या इंका द्वारा दिसंबर 1984 के चुनाव में जीती गई सीटों (415) से कम है. यह जनवरी 1980 के चुनाव में श्रीमती गांधी के नेतृत्व में मिली 353 सीटों से भी कम है. लेकिन संदेश एकदम साफ है कि अगर प्रधानमंत्री अभी मध्यावधि चुनाव कराने का फैसला कर

लोकसभा में इंका की ताकत

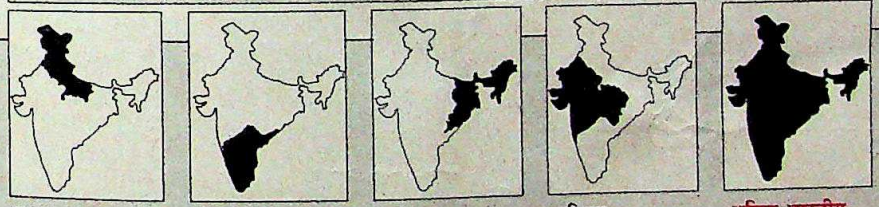

उत्तर
126 सीट

राज्य	सीट
हरियाणा	10
हिमाचल	4
जम्मू-कश्मीर	6
पंजाब	13
उत्तर प्रदेश	85
चंडीगढ़	1
दिल्ली	7

दक्षिण
132 सीटें

राज्य	सीट
आंध्र	42
कर्नाटक	28
केरल	20
तमिलनाडु	39
अंडमान	1
लक्षद्वीप	1
पांडिचेरी	1

पूर्व
142 सीट

राज्य	सीट
अरुणाचल	2
असम	14
बिहार	54
मणिपुर	2
मेघालय	2
मिजोरम	1
नगालैंड	1
ओडीसा	21
सिक्किम	1
त्रिपुरा	2
प बंगाल	42

पश्चिम
142 सीट

राज्य	सीट
गोवा	2
गुजरात	26
मध्य प्रदेश	40
महाराष्ट्र	48
राजस्थान	25
दादर नगर हवेली	1

अखिल भारतीय
542 सीट

	उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	इंका की कुल सीटें	कुल लोकसभा सीटें	सीटों का प्रतिशत
1988 (फरवरी —जनमत सर्वेक्षण)	74	76	86	109	345	542	63.7
1987 (अगस्त —जनमत सर्वेक्षण)	65	79	79	100	323	542	59.6
1984	114	71	96	134	415*	542	76.6
1980	80	95	60	118	353	527	67.0

*1985 में हुए पंजाब और असम के लोकसभा चुनाव के परिणाम शामिल

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लें तो विपक्ष की एक बार फिर धुनाई हो जाएगी.

अगस्त के 323 सीटों के अनुमान में 22 सीटों की वृद्धि का अंदाजा तो पहले भी कई कारणों से था. उस समय राजीव गांधी सरकार एक के बाद एक घटी कई घटनाओं से परेशान हो गई थी. बोफोर्स घोटाले का हंगामा पूरे जोर पर था, अरुण सिंह ने कुछ ही दिन पहले रक्षा राज्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया था और छह महीने तक चली हंगामाई तकरार के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया था.

संकट की यह घड़ी पार करने के बाद इंका को विपक्षी दलों में एकता का कोई लक्षण सामने न आने का भी फायदा मिला है. दरअसल इंडिया टुडे-मार्ग जनमत संग्रह वी.पी. सिंह और उनके जनमोर्चे के लिए भी यह चेतावनी है कि अगर उन्होंने विपक्षी दलों के साथ ठोस और सक्षम गठबंधन नहीं बनाया तो उनका और मोर्चे दोनों का ही बंटाधार हो जाएगा. सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि 79 फीसदी मतदाताओं ने तो जनमोर्चे का नाम भी नहीं सुना है. यहां तक कि हिंदी क्षेत्रों में, जहां वी.पी. सिंह की सभाओं में सबसे अधिक भीड़ जुटती है, 69 फीसदी लोगों ने उसका नाम तक नहीं सुना है.

जनमत संग्रह ने मौजूदा हालात में ही मतदाताओं के मूड का अध्ययन किया है. अगर चुनाव की घोषणा हो जाए तो हो सकता है कि विपक्षी दलों का गठबंधन सामने आ जाए. उस हालत में चुनावी गणित में काफी बदलाव आ जाएगा. तब विपक्षी मतों का बंटवारा भी अब जितना नहीं होगा. इसके अलावा चुनाव के पहले राजनैतिक उठापटक भी तेज रफ्तार से होती है. बदलाव का पता तो चुनाव की घोषणा होने के बाद जनमत संग्रह कराने से हो सकता है और ये तत्व इस जनमत संग्रह में शामिल नहीं हैं.

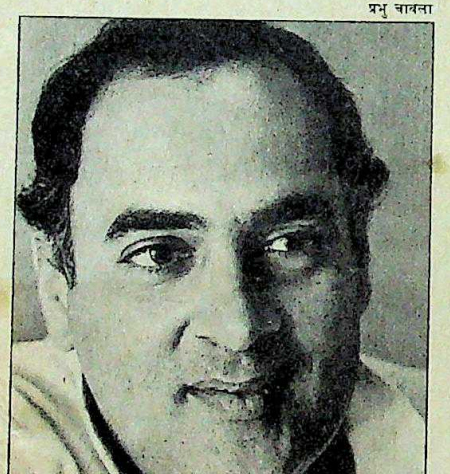
प्रभु चावला

इंडिया टुडे-मार्ग के जनमत संग्रह के नतीजे साफ तौर पर प्रधानमंत्री की छवि में सुधार को दर्शाते हैं. वी.पी. सिंह की चुनौती कमजोर पड़ते जाने से राजीव की छवि बेहतर हुई है. नेतृत्व के मामले में राजीव के मुकाबले सिर्फ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु ही अपनी छह महीने पहले वाली स्थिति को बरकरार रखे हुए हैं.

देश की सबसे बड़ी समस्या के रूप में महंगाई ने अब भ्रष्टाचार से नंबर एक वाली जगह हथिया ली है. वैसे भ्रष्टाचार का मुद्दा अब भी महत्वपूर्ण है, पर आर्थिक स्थिति बहुत खराब हुई है. इसलिए जनमत संग्रह सरकार के लिए भी स्पष्ट चेतावनी है कि आर्थिक स्थिति से नाराजगी और बढ़ेगी.

सरकार जिस तरह से फेयरफैक्स मुद्दे पर काम कर रही है, उसकी भी आलोचना हो रही है. बहुत कम (19 फीसदी) मतदाताओं को ठक्कर-नटराजन आयोग की रिपोर्ट का पता है लेकिन जानने वाले अधिकांश लोग इसे गलत और दुर्भावनापूर्ण मानते हैं. दरअसल बहुमत यह मानता है कि भारतीय लोगों द्वारा विदेश में किए गए घोटालों की जांच के लिए विदेशी एजेंसी की सेवा लेना सही है.

श्रीलंका समझौते को काफी समर्थन मिला है. करीब 70 फीसदी मतदाताओं का मानना है कि श्रीलंका की स्थिति को ठीक से संभाला गया. 70 फीसदी से अधिक लोगों ने सेना भेजने को सही ठहराया. श्रीलंका से सेना वापस बुलाई जाए या नहीं, इस पर दुविधा जरूर थी. आम उम्मीद के विपरीत तमिलनाडु में भी राजीव की श्रीलंका नीति पर जनमत राष्ट्रीय औसत के करीब ही है.

प्रधानमंत्री का कामकाज

		अच्छा	औसत	खराब
उत्तर		28	39	33
दक्षिण		49	37	14
पूर्व		33	34	33
पश्चिम		52	33	15
अखिल भारतीय	फर. 88	43	35	22
	अग. 87	34	37	29

(पता नहीं' शामिल नहीं है) (सभी आंकड़े प्रतिशत में)

प्रधानमंत्री की स्थिति सुधरी

▲ 43 फीसदी मतदाताओं का मानना है कि पिछले छह महीनों में राजीव गांधी का प्रधानमंत्री के रूप में कामकाज 'अच्छा' रहा. अगस्त 1987 में उनके काम को अच्छा कहने वालों की संख्या '34' फीसदी ही थी. अधिक नाराजगी अभी भी उत्तर में बनी हुई है.

राजीव के कामकाज को औसत मानने वाले लोगों की संख्या अगस्त के सर्वे में आए आंकड़ों के आसपास ही है जबकि उनके कामकाज को कमजोर बताने वालों की संख्या अगस्त के 29 से घटकर 22 फीसदी हो गई है.

▼ जनमत संग्रह इस अवधारणा को मजबूत करता है कि प्रधानमंत्री राजनैतिक संकटों से उबर गए हैं. जब मतदाताओं से राजीव गांधी के कामकाज के बारे में पूछा गया तो 36 फीसदी ने कहा कि वे हमारी उम्मीद से बेहतर साबित हुए हैं, 32 फीसदी का मानना है कि उन्होंने उम्मीदों पर पानी फेरा है. प्रधानमंत्री के कामकाज के बारे में बेहतर राय जरूर बनी है पर कुल मिलाकर अभी भी यह उत्तर और पूर्व में ऋणात्मक है (जैसा कि अगस्त में था) जबकि दक्षिण और पश्चिम में धनात्मक है और यह बात इंका के लोगों को बहुत भरोसा दिला सकती है.

प्रधानमंत्री का कामकाज बनाम उम्मीदें

		उम्मीद से बेहतर	उम्मीद से बुरा	उम्मीद के अनुसार
उत्तर		35	41	24
दक्षिण		48	21	31
पूर्व		21	49	30
पश्चिम		38	25	37
अखिल भारतीय	फर. 88	36	32	32
	अग. 87	30	40	30

(पता नहीं' शामिल नहीं है) (सभी आंकड़े प्रतिशत में)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कौन बेहतर प्रधानमंत्री साबित होगा?

	राजीव गांधी	वी.पी. सिंह	राजीव गांधी	रामकृष्ण हेगड़े	राजीव गांधी	ज्योति बसु
उत्तर	56	36	76	22	76	21
दक्षिण	77	16	70	22	75	18
पूर्व	55	28	64	22	41	50
पश्चिम	77	17	87	11	87	10
अखिल भारतीय फर.	68	23	75	18	68	26
अखिल भारतीय अग. 87	61	34	66	30	70	27
इंका के मतदाता	86	10	91	5	85	11
विपक्ष के मतदाता	44	41	45	45	35	58

('पता नहीं' शामिल नहीं है. भेष प्रतिशत दोनों को बराबर मानता है)

(सभी आंकड़े प्रतिशत में)

राजीव की बढ़त में वृद्धि

इंडिया टुडे-मार्ग ने प्रधानमंत्री को मिलने वाली विपक्षी नेताओं की चुनौती को भी मापने की कोशिश की. मतदाताओं से पूछा गया कि राजीव गांधी और वी.पी. सिंह में से कौन बेहतर प्रधानमंत्री साबित होगा. बाद में उनसे राजीव के मुकाबले रामकृष्ण हेगड़े और ज्योति बसु की तुलना करने को भी कहा गया.

प्रधानमंत्री अभी भी सभी विपक्षी नेताओं से आगे चल रहे हैं. अगस्त 1987 के मुकाबले राजीव ने रामकृष्ण हेगड़े और वी.पी. सिंह की तुलना में अपनी छवि बेहतर बनाने में कामयाबी पाई है. लेकिन ज्योति बसु ने राजीव से फासले को थोड़ा कम किया है. इस प्रकार लगता है कि वी.पी. सिंह की चुनौती भोथरी पड़ती जा रही है.

प्रधानमंत्री को शायद इस बात से अधिक किसी और चीज से खुशी नहीं होगी कि उन्होंने उत्तर में भी वी.पी. सिंह से काफी बढ़त हासिल कर ली है. यह अगस्त के 7 फीसदी से बढ़कर 20 फीसदी हो गया है. दरअसल राजीव ने देश के चारों क्षेत्रों में वी.पी. सिंह की तुलना में अपनी स्थिति बेहतर कर ली है.

दक्षिण में रामकृष्ण हेगड़े की चुनौती भी मद्धिम पड़ी है. राजीव गांधी ने अगस्त के चार फीसदी की जगह अब उनसे 48 फीसदी की बढ़त हासिल कर ली है. अब तो सिर्फ मार्क्सवादी ज्योति बसु ही अपना किला बचाए रखने में सफल दिखते हैं. अगस्त में उन्हें मात्र एक फीसदी की बढ़त हासिल थी जो अब नौ फीसदी हो गई है.

छह महीने में कानून-व्यवस्था की स्थिति

	सुधरी	बिगड़ी	यथावत
उत्तर	22	48	30
दक्षिण	27	39	34
पूर्व	20	53	27
पश्चिम	24	46	30
अखिल भारतीय फर. 88	24	46	30
अखिल भारतीय अग. 87	19	53	28

('पता नहीं' शामिल नहीं है)

(सभी आंकड़े प्रतिशत में)

व्यवस्था में सुधार

▲ मतदाताओं को लगता है कि पिछले छह महीनों में कानून और व्यवस्था की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है. पिछली बार 19 फीसदी लोगों को स्थिति में सुधार लग रहा था. इस बार यह संख्या 24 फीसदी हो गई है. हालत बिगड़ी है, यह मानने वालों की संख्या 53 फीसदी से घटकर 46 फीसदी रह गई.

महंगाई ही असली मुद्दा

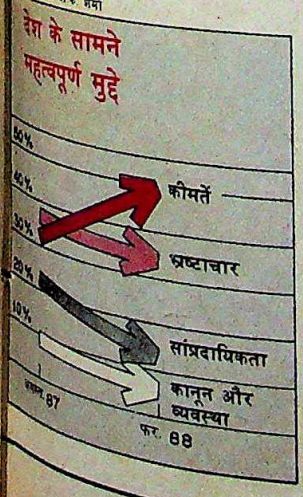

◄ अगस्त में हुआ जनमत संग्रह बोफोर्स के हंगामे के बीच हुआ था और मतदाताओं ने भ्रष्टाचार को देश की सबसे बड़ी समस्या माना था. पर सूखे ने भ्रष्टाचार को दूसरे नंबर पर पहुंचा दिया है (इस बार सूखा 48 फीसदी मत पाकर पहले पर है जबकि पिछली बार इसे 32 फीसदी मत ही मिले थे) 34 फीसदी मतदाताओं ने भ्रष्टाचार को मुख्य मुद्दा माना. पिछले जनमत संग्रह में यह 36 प्रतिशत था.

► अगस्त में 36 फीसदी लोगों ने ही महंगाई को अपनी मुख्य समस्या माना था लेकिन अब ऐसा मानने वालों की संख्या 48 फीसदी हो चुकी है. बेरोजगारी (29 फीसदी) दूसरे स्थान पर मौजूद है. फिर पानी और बिजली का नंबर आता है. पिछले जनमत सग्रह में उत्तर और पश्चिम में ही महंगाई को सबसे बड़ी समस्या माना गया था. इस बार चारों क्षेत्रों में यही सबसे प्रमुख मुश्किल बनकर सामने आई है.

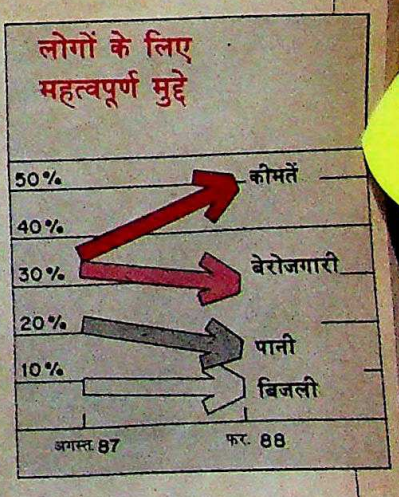

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अभी मंदी, भविष्य अंधकारमय

▼ यह बात ध्यान देने लायक है कि सूखे की मार के कारण अर्थव्यवस्था की विकास दर बहुत नीचे चली गई है और महंगाई के असर ने कमर तोड़ दी है, फिर भी अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति के बारे में मतदाताओं की राय में पिछले छह महीनों में कोई खास अंतर नहीं आया है.

मतदाताओं का छठा हिस्सा मानता है कि अर्थ-व्यवस्था की स्थिति ठीक है, जबकि एक-तिहाई इसे औसत मानते हैं. लेकिन अधिकांश (51 फीसदी) मानते हैं कि अर्थव्यवस्था की हालत खराब है. अगस्त के जनमत संग्रह की तरह ही उत्तरी और पूर्वी राज्यों के मतदाता आर्थिक स्थिति से सबसे अधिक नाराज हैं.

लेकिन मतदाताओं का मन बहुत नरम है और वे मानते हैं कि आगे अर्थव्यवस्था की स्थिति सुधर जाएगी. 31 फीसदी मानते हैं कि उनकी आर्थिक हालत अगले छह महीनों में सुधरेगी. हालत खराब होगी, ऐसा मानने वालों की संख्या सिर्फ 28 फीसदी थी. ऐसा महगाई की मार और देश के कई हिस्सों में पड़े भयंकर सूखे के बावजूद है. छह महीने पहले के जनमत संग्रह से हालत सुधरने और बिगड़ने की उम्मीद करने वालों का प्रतिशत (32 और 28) करीब-करीब यही था. दोनों जनमत संग्रहों में सबसे बड़ा तबका (40 और 41 फीसदी) यही मानता है कि अगले छह महीनों में हालत वैसी ही रहेगी.

अर्थव्यवस्था

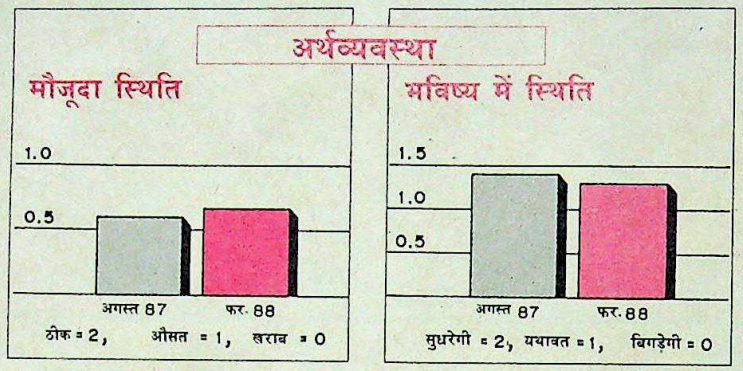

अर्थव्यवस्था की स्थिति

		बढ़िया	औसत	खराब
उत्तर		12	26	62
दक्षिण		19	39	42
पूर्व		14	25	61
पश्चिम		20	34	46
अखिल भारतीय	फर. 88	17	32	51
	अग. 87	16	31	53

('पता नहीं' शामिल नहीं है) (सभी आंकड़े प्रतिशत में)

अर्थव्यवस्था का भविष्य

		सुधरेगी	खराब होगी	ऐसी ही रहेगी
उत्तर		34	37	29
दक्षिण		32	18	50
पूर्व		18	35	47
पश्चिम		40	26	34
अखिल भारतीय	फर. 88	31	28	41
	अग. 87	32	28	40

('पता नहीं' शामिल नहीं है) (सभी आंकड़े प्रतिशत में)

चेतना की कमी

▼ अपने आसपास घट रही घटनाओं की मतदाताओं को कितनी खबर होती है? अगर उन्हें बहुत कुछ और पूरे विस्तार से बातें मालूम नहीं रहती तो भारतीय मतदाता (अधिकांश अशिक्षित) कैसे इतनी होशियारी और एकमत से अगले पांच वर्षों के लिए अपनी सरकार का चुनाव करते हैं? इन सवालों के जवाब आसान नहीं हैं लेकिन इस जनमत संग्रह ने लोगों की जागरूकता के कुछ दिलचस्प उदाहरण भी दिए हैं. जैसे ठक्कर-नटराजन आयोग की रिपोर्ट की तुलना में राजीव की लक्षद्वीप की छुट्टियों के बारे में अधिक लोगों (19 के मुकाबले 31 फीसदी) को पता था. वी.पी. सिंह का जनमोर्चा भी इस मामले में पिछड़ गया है. उसे 21 फीसदी लोग ही जानते हैं और पूर्व में तो उसका नाम सिर्फ 11 फीसदी लोगों ने सुना है जबकि पश्चिम में 16 फीसदी ने.

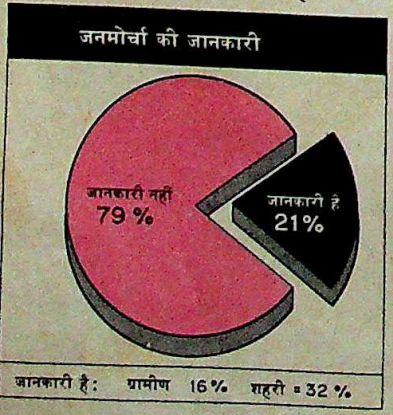

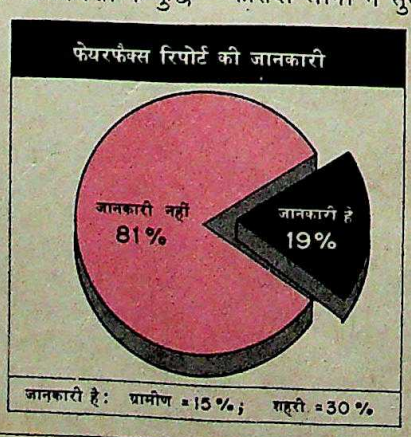

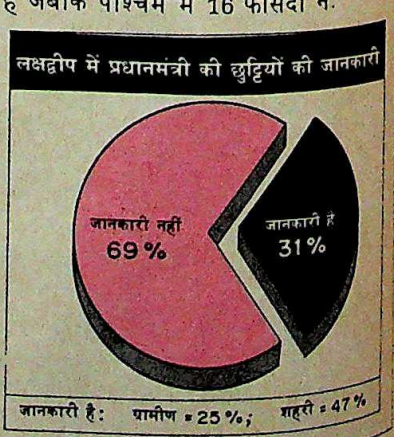

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

श्रीलंका—सेना भेजने का फैसला

	अच्छा फैसला	नहीं फैसला
उत्तर	69	31
दक्षिण	73	27
पूर्व	67	33
पश्चिम	75	25
अखिल भारतीय	72	28
तमिलनाडु	73	27

('पता नहीं' शामिल नहीं है) (सभी आंकड़े प्रतिशत में)

श्रीलंका: पक्का समर्थन

▲ श्रीलंका में सैंकड़ों सैनिकों के मरने के बावजूद भारतीय सेना पिछले छह महीनों से उस देश में डटी हुई है. लगता है कि वहां उसकी संख्या अभी और बढ़ाई जाएगी. वहां सेना भेजने के नाजुक सवाल पर 72 फीसदी लोग मानते हैं कि सरकार ने यह कदम उठाकर ठीक किया है. हैरानी की बात यह है कि तमिलनाडु में ऐसी राय रखने वालों का अनुपात 73 फीसदी है. इस मामले में सरकारी नीति को सबसे जबरदस्त समर्थन पश्चिमी क्षेत्र (75 फीसदी) से मिला लेकिन अन्य क्षेत्रों में भी कोई खास अंतर नहीं था.

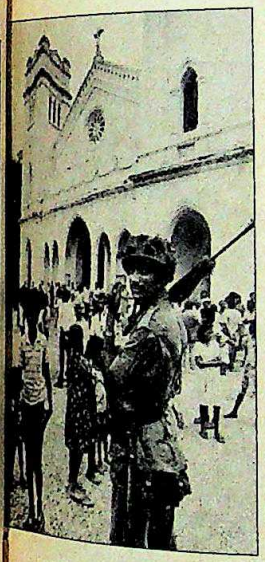

70 फीसदी से कुछ अधिक लोग मानते हैं कि सरकार ने श्रीलंका समस्या को ठीक से संभाला है. तमिलनाडु में भी 61 फीसदी लोगों की यही राय थी. भारतीय सैनिकों के मारे जाने की खबरें मतदाताओं तक भी पहुंचने लगी हैं इसलिए करीब आधे लोग मानते हैं कि अब भारतीय सेना को अब श्रीलंका से वापस आ जाना चाहिए.

शांति सेना वापस बुलानी चाहिए?

	वापस आए	नहीं
उत्तर	49	51
दक्षिण	45	55
पूर्व	41	59
पश्चिम	55	45
अखिल भारतीय	48	52
तमिलनाडु	49	51

('पता नहीं' शामिल नहीं है) (सभी आंकड़े प्रतिशत में)

गरीब समर्थक छवि

▼ भारतीय राजनीति का यह नियम-सा बन चुका है कि राजनेताओं को 'गरीब समर्थक' दिखना चाहिए. इस मामले में राजीव की छवि अमीर समर्थक (33 फीसदी) की जगह गरीब समर्थक (55 फीसदी) ही अधिक है. विपक्ष का समर्थन करने वाले मतदाता भी सरकार को अमीर समर्थक (56 फीसदी) ही मानते हैं.

राजीव की नितियां

	गरीब समर्थक	धनी समर्थक	दोनों नहीं
उत्तर	49	39	12
दक्षिण	62	22	16
पूर्व	34	50	16
पश्चिम	71	23	6
अखिल भारतीय	55	33	12
इंका के मतदाता	72	18	10
विपक्ष के मतदाता	34	56	10

('पता नहीं' शामिल नहीं है) (सभी आंकड़े प्रतिशत में)

फेयरफैक्स

रिपोर्ट सही थी या एकपक्षीय?

	सही	गलत
अखिल भारतीय	39	61

विदेशी एजेंसियों को नियुक्ति करना?

	सही	गलत
अखिल भारतीय	60	40

('पता नहीं' शामिल नहीं है) (सभी आंकड़े प्रतिशत में)

फेयरफैक्स रिपोर्ट पक्षपातपूर्ण

▲ 81 फीसदी मतदाताओं ने तो ठक्कर-नटराजन आयोग की रिपोर्ट के बारे में सुना भी नहीं था. यह स्तर राजनैतिक रूप से चेतन पूर्व में (26 फीसदी) राष्ट्रीय औसत (19 फीसदी) से ऊपर था.

जिन लोगों को रिपोर्ट के बारे में पता था उनसे पूछा गया कि वे इसे कैसा मानते हैं. 39 फीसदी को इसमें कोई दोष नजर नहीं आया पर 61 फीसदी इसे पक्षपातपूर्ण मानते हैं.

सभी मतदाताओं से विदेशों में भारतीय लोगों द्वारा वित्तीय गड़बड़ी करने के आरोप की जांच के लिए विदेशी एजेंसी की सेवा लेने के बारे में राय पूछी गई. जस्टिस ठक्कर और नटराजन की राय के विपरीत 60 फीसदी लोग ऐसा करने के पक्ष में थे. ऐसे कदम का समर्थन उत्तर में काफी अधिक (84 फीसदी) था. यह शायद वी.पी. सिंह के उत्तर में अधिक प्रभाव के कारण हो.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

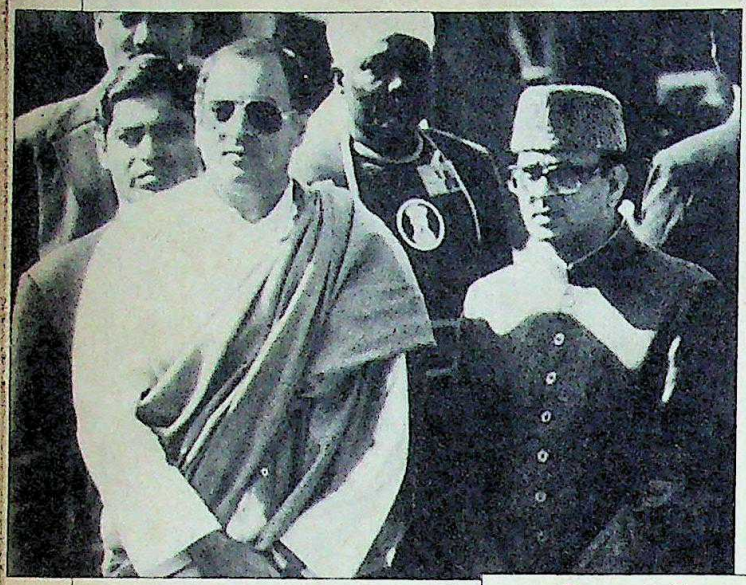

वी.पी. सिंह के लिए चेतावनी

▼ मतदाताओं के मन में राजीव गांधी और वी.पी. सिंह की क्षमताओं के बारे में क्या विचार हैं, यह जानने के लिए कई सवाल रखे गए. इनमें यह सवाल भी था कि असली 'मि. क्लीन' कौन है.

और देश भर में प्रधानमंत्री स्पष्ट रूप से ऐसे व्यक्ति के रूप में सामने आए जो वी.पी. सिंह के मुकाबले

- अधिक ईमानदार हैं;
- बेहतर प्रशासक हैं;
- स्पष्ट दृष्टि वाले हैं; और
- अधिक गरीब समर्थक हैं;

वी.पी. सिंह अपने इलाके, उत्तर और कुछ अधिक राजनैतिक चेतन माने जाने वाले पूर्व (जिसमें प. बंगाल और बिहार शामिल हैं) में थोड़ा अधिक मत हासिल करने में सफल रहे.

इंका समर्थकों के बीच वी.पी. सिंह राजीव के आगे कहीं नहीं ठहरते. हां विपक्ष को वोट देने वालों के लिए वी.पी. सिंह राजीव से अधिक ईमानदार जरूर हैं.

राजीव गांधी बनाम वी.पी. सिंह

अधिक ईमानदार

	राजीव गांधी	वी.पी. सिंह	राजीव की बढ़त
उत्तर	47	37	+10
दक्षिण	70	21	+49
पूर्व	46	34	+12
पश्चिम	75	17	+58
अखिल भारतीय	**62**	**25**	**+37**
हिंदी इलाके में	56	30	+26
हिंदी इलाके के बाहर	67	21	+46
इंका के मतदाता	79	12	+67
विपक्ष के मतदाता	39	49	−10

('पता नहीं' शामिल नहीं है. शेष प्रतिशत दोनों को बराबर मानता है) (सभी आंकड़े प्रतिशत में)

बेहतर प्रशासक

	राजीव गांधी	वी.पी. सिंह	राजीव की बढ़त
उत्तर	57	38	+19
दक्षिण	72	15	+57
पूर्व	54	31	+23
पश्चिम	80	16	+64
अखिल भारतीय	**68**	**23**	**+45**
हिंदी इलाके में	65	28	+37
हिंदी इलाके के बाहर	70	19	+51
इंका के मतदाता	84	11	+73
विपक्ष के मतदाता	45	44	+1

('पता नहीं' शामिल नहीं है. शेष प्रतिशत दोनों को बराबर मानता है) (सभी आंकड़े प्रतिशत में)

अधिक स्पष्ट दृष्टि

	राजीव गांधी	वी.पी. सिंह	राजीव की बढ़त
उत्तर	56	37	+19
दक्षिण	72	13	+59
पूर्व	54	30	+24
पश्चिम	80	16	+64
अखिल भारतीय	**68**	**22**	**+46**
हिंदी इलाके में	66	28	+38
हिंदी इलाके के बाहर	70	18	+52
इंका के मतदाता	83	11	+72
विपक्ष के मतदाता	46	42	+4

('पता नहीं' शामिल नहीं है. शेष प्रतिशत दोनों को बराबर मानता है) (सभी आंकड़े प्रतिशत में)

अधिक गरीब समर्थक

	राजीव गांधी	वी.पी. सिंह	राजीव की बढ़त
उत्तर	59	30	+29
दक्षिण	75	12	+63
पूर्व	50	25	+25
पश्चिम	85	11	+74
अखिल भारतीय	**70**	**18**	**+52**
हिंदी इलाके में	66	22	+44
हिंदी इलाके के बाहर	74	14	+60
इंका के मतदाता	85	8	+77
विपक्ष के मतदाता	45	37	+8

('पता नहीं' शामिल नहीं है. शेष प्रतिशत दोनों को बराबर मानता है) (सभी आंकड़े प्रतिशत में)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वी.पी. सिंह के जनमोर्चा का राजनैतिक झुकाव

	वामपंथ की ओर झुकाव	दक्षिणपंथ की ओर झुकाव	मध्यमार्गी
उत्तर	33	51	16
दक्षिण	26	26	48
पूर्व	46	34	20
पश्चिम	23	45	32
अखिल भारतीय	33	39	28

('पता नहीं' शामिल नहीं है) (सभी आंकड़े प्रतिशत में)

दक्षिणपंथी रुझान?

▲ कई महीने पहले वी.पी. सिंह ने जनमोर्चा का गठन किया. इंका के कर्ताधर्ताओं को इस बात से राहत महसूस होगी कि 79 फीसदी मतदाताओं ने जनमोर्चा का नाम ही नहीं सुना है. राजनैतिक रूप से अधिक जागरूक उत्तरी क्षेत्र के 69 फीसदी मतदाताओं ने भी जनमोर्चा का नाम नहीं सुना है.

वी.पी. सिंह ने समाजवादी छवि बनाने की भरपूर कोशिश की है. लेकिन इसके बावजूद सिर्फ 33 फीसदी मतदाताओं को ही वे और उनका जनमोर्चा वामपंथी रुझान वाला लगता है जबकि 39 फीसदी लोग उसे दक्षिणपंथी रुझान वाला मानते हैं.

लक्षद्वीप में प्रधानमंत्री की छुट्टी

▼ बच्चन परिवार और सोनिया गांधी के रिश्तेदारों के साथ प्रधानमंत्री द्वारा लक्षद्वीप में साल के आखिर में छुट्टियां मनाने पर अखबार-पत्रिकाओं में काफी कुछ छपा था. लेकिन 69 फीसदी मतदाताओं को इस की खबर भी नहीं थी. प्रधानमंत्री को इस तरह छुट्टी मनाने का हक है या यह सार्वजनिक पैसे का दुरुपयोग है, इस मुद्दे पर विभाजन बहुत तीखा था (51 फीसदी पक्ष में, 49 विपक्ष में). पूर्व के 62 फीसदी मतदाताओं का मानना था कि यह सार्वजनिक पैसे की बर्बादी है जबकि उत्तर के 61 फीसदी और दक्षिण के 58 फीसदी मतदाता प्रधानमंत्री के छुट्टी मनाने को सही मानते हैं.

लक्षद्वीप में प्रधानमंत्री का छुट्टी मनाना

	प्रधानमंत्री को छुट्टी मनाने का हक	पैसे की बर्बादी
उत्तर	61	39
दक्षिण	58	42
पूर्व	38	62
पश्चिम	49	51
अखिल भारतीय	51	49

('पता नहीं' शामिल नहीं है) (सभी आंकड़े प्रतिशत में)

शहरी-ग्रामीण विभाजन

▼ इंडिया टुडे-मार्ग के जनमत संग्रह की खास बात ग्रामीण इलाकों को काफी बड़े पैमाने पर शामिल करना है. 7,500 से अधिक ग्रामीण मतदाताओं की राय पूछी गई. और जब ग्रामीण इलाकों के परिणामों की तुलना शहरों से करते हैं तो यह महत्वपूर्ण अंतर सामने आता है कि राष्ट्रीय जनमत को प्रतिबिंबित करने के लिए ग्रामीण मतदाताओं (कम-से-कम 75 फीसदी) को शामिल करना कितना जरूरी है.

प्रधानमंत्री गांवों में अधिक लोकप्रिय हैं (गांवों के 45 फीसदी लोग उन्हें 'अच्छा' मानते हैं जबकि शहर में 37 फीसदी). ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए भ्रष्टाचार कम बड़ा मुद्दा है और यहां वी.पी. सिंह पर राजीव की बढ़त अधिक बड़ी है.

राजीव का कामकाज: ग्रामीण/शहरी

	अच्छा	औसत	बुरा
ग्रामीण	45	33	22
शहरी	37	40	23

('पता नहीं' शामिल नहीं है) (सभी आंकड़े प्रतिशत में)

मुख्य मुद्दे: शहरी ग्रामीण विभाजन

	सांप्रदायिकता	कानून-व्यवस्था	मंहगाई	भ्रष्टाचार
ग्रामीण	10	6	52	32
शहरी	16	7	40	37

('पता नहीं' शामिल नहीं है) (सभी आंकड़े प्रतिशत में)

परंपरागत आधार

▶ प्रधानमंत्री ने भले ही शुरुआत मध्यमवर्ग की जरूरतों को पूरा करने से की थी पर अब वे तेजी से कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक: हरिजन, मुसलमान और महिलाओं की ओर ध्यान देने लगे हैं. मुस्लिम महिला विधेयक वगैरह इसके संकेत थे. इंका को वोट देने में ये तबके आम औसत के मुकाबले सदा से आगे रहे हैं.

पिछले कुछ वर्षों में जो अनेक जनमत संग्रह हुए हैं जिससे यह बात सामने आई है कि इंका को मर्दों के बजाय औरतों का अधिक समर्थन मिलता है. इस जनमत संग्रह से भी इसी बात की पुष्टि होती है. इससे यह पता भी चलता है कि नौजवान लोग वयस्क और बूढ़ों की तुलना में इंका को अधिक चाहते हैं. इसका कारण शायद प्रधानमंत्री की इमेज नौजवान की होना है.

इंका के समर्थन का आधार

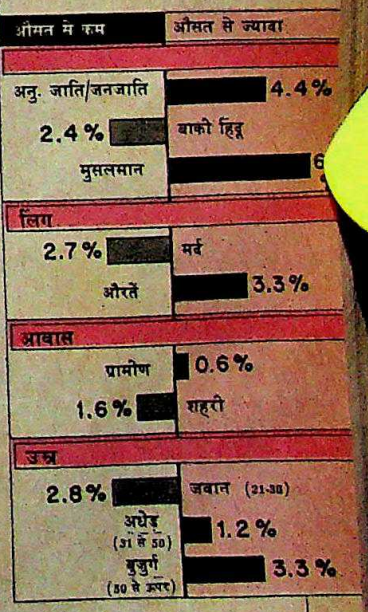

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

त्रिपुरा

इंका की बदली किस्मत

पर अत्यल्प बहुमत सरकार के सामने मुश्किलें भी बहुत हैं

पिछले पखवाड़े त्रिपुरा और मेघालय में हुए विधानसभा चुनावों में उत्तर-पूर्व के इन राज्यों के भाग्य ने पलटा खाया. भड़कती हुई जातीय हिंसा और तनावों के बीच हुई इस कांटे की टक्कर में इंका गठबंधन ने वामपंथी सरकार के एक दशक से चले आ रहे शासन को समाप्त कर दिया. इसी प्रकार मेघालय में एक कमजोर गठबंधन सत्ता में आया. इंडिया टुडे के संवाददाताओं ने चुनाव के दौरान इन क्षेत्रों का दौरा किया और प्रमुख व्यक्तियों से बातचीत की. उनकी रिपोर्ट:

कुछ चटखते अंगारों के अलावा चिताओं की सिर्फ राख ही बची थी. चिताओं से निकलती धुएं की पतली लकीरें कुछ ही गज दूर मतदान केंद्र पर धैर्य से लाइन में खड़े लोगों की गुस्से से भरी आंखों को भेद रही थीं. क्या कुछ होने जा रहा है, यह बिलकुल स्पष्ट नजर आ रहा था. दक्षिणी त्रिपुरा के गबारदी गांव के लोगो ने सरकार को उखाड़ फेंकने का फैसला कर लिया था, क्योंकि यह सरकार मतदान से एक ही दिन पहले उनके गांव पर धावा बोलकर 11 लोगों की हत्या कर देने वाले काले वेशधारी वनवासी छापामारों से उनकी रक्षा कर पाने में सरासर नाकाम रही थी. 31 वर्षीया राधा रानी, जिनका भाई भी मारा गया, कहती हैं, "हम सबने इंका को वोट दिया. ऐसी सरकार को वोट देने से क्या लाभ जो हमारी जान भी नहीं बचा सकती."

छिटपुट जंगलों वाले गांवों और कस्बों से बने त्रिपुरा में हर कहीं वाम मोर्चा सरकार से यही सवाल किया जा रहा था. वैसे महीना भर पहले ही वाम मोर्चा सरकार ने दावा किया था कि वह तीसरी बार जीत हासिल करने जा रही है. पर चुनाव के पहले वाले पखवाड़े भर में ही 70 लोगों को, जिनमें अधिकांश बहुसंख्यक बंगाली थे, ट्राइबल नेशनल वालंटियर्स (टीएनवी) बागियों ने भून डाला. चुनाव से ठीक पहले राज्य को गड़बड़ी वाला क्षेत्र घोषित किया गया और सेना बुला ली गई. हिंसा पर काबू पाने में वाम मोर्चे की विफलता ने इंका को वह जीत दिला दी जो महीने भर पहले लगभग असंभव ही लग रही थी.

राज्य की 30 फीसदी वनवासी आबादी की वकालत करने वाली त्रिपुरा उपजाति जुबा समिति (टीयूजेएस) के साथ मिलकर इंका ने 60 सदस्यों वाले सदन में 31 सीटें हासिल कर लीं. माकपा और उसकी सहयोगी पार्टियां सिर्फ दो स्थानों से पिछड़कर 28 पर ही रुक गईं. राजनैतिक केंद्रीकरण इतना तीव्र था कि उग्रपंथी 'आमरा बंगाली', भाजपा और जनता पार्टी समेत बाकी सभी दलों का पत्ता ही साफ हो गया. इन सभी के उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो गईं. पिछले चुनाव में इंका-टीयूजेएस मोर्चे को 17 सीटें मिलीं थीं जबकि माकपा-रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी गठबंधन को 40 सीटें मिली थीं.

चुनाव में इंका को नकारात्मक वोट भी मिले. चुनाव से ठीक पहले टीएनवी द्वारा की गई हत्याओं से लोगों में असुरक्षा की लहर फैल गई थी

पर किस्मत बदलने के बावजूद नए मुख्यमंत्री

नक्शा: बी के शर्मा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सुधीररंजन मजूमदार

'टीएनवी का खात्मा करेंगे'

इंका में आने से पहले स्कूल मास्टर रहे 49 वर्षीय सुधीररंजन मजूमदार से वरिष्ठ संवाददाता **रमेश मेनन** *ने उनके अगरतला निवास पर भेंट की. इसी बातचीत के कुछ अंश:*

● ***आप सबसे पहले कौन-सा और क्या काम करना चाहते हैं?***

शांति कायम करना. वाम मोर्चे ने कानून और व्यवस्था का मामला एकदम उलझाकर रख दिया है.

शपथ लेते हुए मजूमदार

रमेश मेनन

● ***इंका-टीयूजेएस मोर्चा बनने के बाद क्या इस बात की संभावना है कि टीएनवी खुली राजनीति शुरू करेगी?***

उनमे कोई बातचीत नहीं होगी. हम उनका खात्मा करके ही रहेंगे. राजीव जी ने पहले ही यह बात कह दी है.

● ***आपका चुनाव सर्वसम्मति से हुआ या और भी दावेदार थे?***

सर्वसम्मति से हुआ. हो सकता है और दावेदार भी रहे हों.

● ***एकदम अनुभवहीन मंत्री विधानसभा में माकपा का मुकाबला कैसे करेंगे?***

चुनाव में उन्हें हटा सकते हैं तो साबित होता है कि हम उतने कमजोर नहीं हैं. हमारा कामकाज बढ़िया रहेगा.

● ***आपके चुनावी वादों को पूरा करने में तो बड़ी रकम लगेगी क्योंकि इसमें कर्ज मेले, औद्योगीकरण करना, रेलवे बिछाना और संचार व्यवस्था तैयार करना शामिल है. यह रकम कहां से आएगी?***

हम अपने वादे धीरे-धीरे पूरे करेंगे. पैसा केंद्र देगा, जो अब त्रिपुरा में काफी हद तक दिलचस्पी लेने लगा है.

सुधीररंजन मजूमदार बंगाली-बहुल इंका और वनवासी-बहुल टीयूजेएस के कमजोर गठबंधन के भरोसे ही गद्दीनशीन हो सके हैं. विपक्ष में आया वाम मोर्चा सत्तारूढ़ गठबंधन की इस विचित्र जातीय विसंगति से फायदा उठाने की ताक में बैठा है तो वनवासी छापामारों की हिंसक गतिविधियां भी रुकने का नाम नहीं ले रही हैं. ऐसे में लगता है कि राज्य अनिश्चितता के एक नए दौर में प्रविष्ट हो गया है.

स्थानीय पेचीदगियों को जरा दरकिनार करके देखें तो पता चलता है कि 24 लाख की आबादी वाले इस राज्य में इंका की जीत का देशव्यापी असर हुआ है. इंका के चुनाव अभियान का संचालन करने वाले केंद्रीय संचार राज्यमंत्री संतोष मोहन देव ने कहा, "यह राजीव की जीत है. और इससे उन आलोचकों का मुंह बंद हो जाना चाहिए जो उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे." इससे राजीव के इस्तीफे की मांग को लेकर हाल में दिल्ली में विशाल प्रदर्शन करने वाले वाम मोर्चे को भी एक झटका लगा है.

इंका की जीत में संयोग का भी कुछ हाथ था और दिल्ली में बैठे नेताओं की जोड़-तोड़ का भी. 1987 में टीएनवी ने कुल 109 लोगों को मारा जिसमें से 79 लोग साल के अंतिम हफ्ते में ही मारे गए. इस दौरान न तो कोई आतंकवादी मारा गया न पकड़ा गया. सो राज्य के लोग एकदम कांप उठे. यह सब राज्य पुलिस की मदद के लिए आए अर्द्धसैनिक बलों के 1800 सैनिकों के रहने के बावजूद हुआ. त्रिपुरा पुलिस ने 1987 में राज्य की अपराध की स्थिति की जो समीक्षा की थी उसके अनुसार राज्य में सिर्फ 232 टीएनवी छापामार हैं जिनमें से 48 पिछले छह वर्षों में पकड़े जा चुके हैं. वाम मोर्चा सरकार ने आतंकवाद विरोधी कानून को अलोकतांत्रिक मानते हुए लागू नहीं किया और नतीजा यह हुआ कि ये सारे आतंकवादी छूट गए.

इससे वाम मोर्चा सरकार और बहुसंख्यक (70 फीसदी) बंगालियों के बीच दरार बढ़ती गई. प्रधानमंत्री ने अपने चुनावी भाषणों में टीएनवी की गतिविधियों पर रोक न लगा पाने में वाम मोर्चा सरकार की असफलता को मुख्य मुद्दा बनाया. आतंकवादियों से मिजोरम की तर्ज पर कोई समझौता न करने की उनकी घोषणा से भी मतदाता प्रभावित हुए. उन्होंने सभाओं में कहा, "हम टीएनवी को समाप्त कर देंगे. वे लोग निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं और हम ऐसे लोगों से कोई बात नहीं करते."

29 जनवरी को राजीव गांधी जैसे ही राज्य की तूफानी चुनावी यात्रा पूरी करके दिल्ली लौटे, राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया और सेना से स्थिति संभालने को कह दिया गया. ऐसा करने का इससे बढ़िया मौका और नहीं हो सकता था. राज्य को काफी समय से अशांत क्षेत्र घोषित करने की मांग करने वाले इंका नेताओं को बंगालियों से यह कहने का मौका मिल गया कि उनकी पार्टी टीएनवी से सख्ती बरतने के पक्ष में है और मार्क्सवादी राजनैतिक समाधान की बात करके नरम रुख अपनाते रहे हैं. इस बात का अपेक्षित असर हुआ तथा इंका को बंगाली-बहुल इलाकों—रामनगर, धरमनगर, कदमतला और खोवाई वगैरह में अच्छा समर्थन मिला गया.

राजनैतिक प्रेक्षकों का मानना है कि अगर सेना नहीं आती तो आधे लोग भी वोट डालने नहीं जाते. टीएनवी ने चुनाव के बहिष्कार की घोषणा कर रखी थी और इससे चुनाव के दिन भारी खून-खराबा होने की आशंका थी. पर सेना के 8,000 और अर्द्धसैनिक बलों के 22,000 जवान राज्य भर में फैल गए. इससे मतदाताओं की हिम्मत बंधी. मतदान 75 फीसदी हुआ. यह बात इंका के हक में गई. अगरतला के 38 वर्षीय माकपा कार्यकर्ता नेपाल सेनगुप्त ने कहा, "आदर्शों और निष्ठा के बावजूद हम हार गए क्योंकि सेना के आते ही बंगाली उधर झुक गए."

पर त्रिपुरा में एकाएक सेना भेजने के केंद्र

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

के फैसले की विपक्षी दलों ने खूब आलोचना की. दिल्ली में बैठक कर रहे विपक्षी मुख्य-मंत्रियों ने इसकी निंदा की और वाम मोर्चा ने इसे चुनावी हथकंडा करार दिया. पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने कहा, "सेना इंका की निजी जागीर नहीं है."

त्रिपुरा में आतंकवादी विरोधी अभियान का नेतृत्व करने वाले मेजर जनरल हरजीत सिंह तलवार ने सेना द्वारा इंका की मदद करने के आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की. उन्होंने कहा, "हम यहां एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाने आए हैं और कोई बकवास पसंद नहीं करेंगे. भौंडी राजनैतिक गपबाजी बंद होनी चाहिए." लेकिन उत्तेजना भरे माहौल में सेना की भूमिका निश्चित रूप से राजनैतिक हो जाएगी.

चुनाव के ठीक पहले शांति बहाल करने की केंद्र की मुस्तैदी को भी आलोचक राजनैतिक चोंचलेबाजी मानते हैं. सिर्फ पांच साल पहले ही श्रीमती गांधी की सरकार ने असम के हिंसक चुनाव में यह कहकर सेना नहीं बुलाई थी कि इससे चुनावी प्रक्रिया में बाधा आएगी. तब चुनाव आयोग ने भी कहा था कि सेना की मौजूदगी में स्वतंत्र चुनाव कराना संभव नहीं होगा. फिर मतदान होने तक वहां सेना नहीं भेजी गई. जबकि चुनाव प्रक्रिया में करीब 7,000 लोग मारे गए थे. पर इस बार चुनाव के मौके पर केंद्र ने अपना मतलब साधने के लिए सेना लगा दी.

केंद्र ने इन आरोपों को गलत बताया. उसने कहा टीएनवी की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए वाम मोर्चा सरकार को पर्याप्त समय और मौका दिया गया पर उसमें इच्छा-शक्ति ही नहीं थी. पर पिछले एक दशक से मुख्यमंत्री रहे 82 वर्षीय नृपेन चक्रवर्ती मानते हैं कि सेना बुलाना 'अलोक-तांत्रिक कदम' था. उन्होंने कहा कि राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित करने से पहले प्रधानमंत्री ने उनसे पूछा तक नहीं. चक्रवर्ती अब भी कहते हैं कि इन तरीकों से वनवासियों के मन में यह बात बैठ जाएगी कि गैरवनवासी सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए टीएनवी का रास्ता ही ठीक है.

पर इंका को सिर्फ सेना की मौजूदगी से ही फायदा नहीं हुआ. एक और चुनावी जादू—कर्ज मेला, उसने यहां भी अपनाया. चुनाव से पहले उसने राज्य के 20 फीसदी मतदाताओं (करीब चार लाख) के बीच 75 करोड़ रुपए कर्ज बांटने की योजना बनाई. वाम मोर्चा ने इसका विरोध किया और अगरतला में कर्ज मेले के दौरान हिंसा फूट पड़ी. जिसमें छह लोग मारे गए और 600 घायल हुए. दिसंबर के आखिर में हुए इस कांड को भी राजीव गांधी ने खूब भुनाया. उन्होंने कहा कि वाम मोर्चा दलगत फायदों के लिए गरीब लोगों को कर्ज भी देने नहीं देता.

वाम मोर्चे को कुछ गलतियों की कीमत भी अदा करनी पड़ी. लोगों में इस बात से नाराजगी थी कि अधिकांश सरकारी काम और ठेके माकपा के लोगों को ही मिलते थे. बाद में तो माकपा (सीपीएम) को कुछ लोग कांट्रेक्टर्स पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) कहने लगे थे. संतोष मोहन देव भी मानते हैं, "नौकरी और दूसरे काम देने में वाम मोर्चे की पक्षपातपूर्ण नीतियों ने भी हमें जीतने में बहुत हद तक मदद दी."

ऐसी हालत में माकपा की हार जायज ही लगती है. माकपा को जिन नेताओं की हार से झटका लगा उनमें राजस्वमंत्री खगेन दास, वनमंत्री अराबेर रहमान, खाद्यमंत्री राम-कुमार नाथ, विधानसभा अध्यक्ष अमरेंद्र शर्मा और माकपा केंद्रीय समिति के सदस्य और मुख्य सचेतक माणिक सरकार प्रमुख हैं. और टीएनवी की घोर विरोधी 'आमरा बंगाली' के वोट भी इंका को मिले. इस पार्टी ने 50 जगहों से चुनाव लड़ा था. महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने चुनावी भाषणों में राजीव गांधी ने इस सांप्रदायिक संगठन के खिलाफ कुछ नहीं कहा जबकि पिछले साल हुए वनवासी-विरोधी दंगों के पीछे 'आमरा बंगाली' का ही हाथ रहा है.

राज्य के राजनैतिक रूप से सजग मतदाताओं के लिए इंका को जिताने का एक और कारण था—तेज विकास और अधिक केंद्रीय मदद का लाभ (देखें इंटरव्यू). पर इंका की परीक्षा अभी टीएनवी से निबटने में होगी. मुख्यमंत्री मजूमदार ने कहा, "हम लोग टीएनवी के खात्मे के लिए वचनबद्ध हैं." पर यह आसान काम नहीं होगा. नई सरकार के शपथ लेने के कुछ घंटे बाद ही आतंकवादियों ने पांच बंगालियों को मार डाला.

इसके अलावा अत्यल्प बहुमत से सत्ता में आई और गुटबाजी से ग्रस्त इंका को धाकड़ राजनेता नृपेन चक्रवर्ती के दांवों का भी जवाब देना होगा. उनकी पार्टी का अभी भी काफी बड़ा जनाधार है और संगठन बहुत मजबूत है. उन्होंने कहा भी, "मैंने कांग्रेस के सभी चुनावी वायदों की सूची बनाकर अपने पास रख ली है." ऐसे में इंका को बहुत संभलकर कदम रखने होंगे. उसे टीएनवी से निबटना भी है और यह भी ध्यान रखना है कि उसकी भागीदार टीयूजेएस उसके किसी कदम से नाराज भी न हो. चक्रवर्ती जैसा दिग्गज राजनेता ऐसी स्थिति का लाभ ले सकता है. इस तरह नई सरकार को यह एहसास लगातार रखना होगा कि अभी उसका 'प्रोबेशन' चल रहा है.

—रमेश मेनन, अगरतला में

व्यापक सुरक्षा प्रबंधों के कारण टीएनवी का चुनाव बहिष्कार का नारा नाकाम रहा और 75 फीसदी मतदान हुआ

पी. चक्रवर्ती/यूएनआई/एएफपी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मेघालय

बैसाखी पर टिकी सरकार

इंका की असली अग्निपरीक्षा तो अभी विधानसभा में होगी

शिलंग में पिछले पखवाड़े जब पुरनो अगिडोक संगमा के नेतृत्व में इंका के नए मंत्रिमंडल के सदस्य शपथ ग्रहण के समय फूलकर कुप्पा हो रहे थे तभी राजभवन के सुसज्जित हाल को भूकंप के भारी झटके ने झकझोर दिया. भूकंप का यह झटका इस डावांडोल सरकार के भविष्य का एक सूचक माना जा सकता है. तीन टांग की कुर्सी पर बैठी यह सरकार कुछ निर्दलीय विधायकों और हिल पीपुल्स यूनियन (एचपीयू) के अध्यक्ष ब्रिगटन वुहाई लिंगडोह के 'मौखिक समर्थन' के सहारे टिकी है. लेकिन संगमा ने अपनी खास आदत के साथ खीस निपोरते हुए कहा, "उत्तर-पूर्व में भूकंप आना तो आम बात है और शायद यह हमारे लिए शुभ लक्षण ही साबित हो."

लेकिन अपने गृह राज्य में लौटने के लिए केंद्र में श्रममंत्री का पद छोड़कर जाने वाले 40 वर्षीय संगमा की सरकार को बचे रहने के लिए काफी कुछ करने की जरूरत होगी. छोटे क्षेत्रीय दलों और कुछ निर्दलीय विधायकों का विपक्षी गठबंधन अपने साथ बहुमत होने का दावा कर रहा है. तय है कि 22 फरवरी को विधानसभा सत्र शुरू होते ही विपक्ष के अविश्वास-प्रस्ताव की आग में संगमा सरकार को अग्निपरीक्षा देनी होगी.

इंका के सामने इस मुश्किल का मुख्य कारण यह है कि वह 1983 में कुल 60 सीटों में से 25 सीटों की जीत को भी इस बार दुहरा नहीं पाई. पिछले पखवाड़े हुए मतदान में उसे इससे भी तीन सीटें कम मिलीं.

चुनाव में किसी एक पार्टी को बहुमत न मिलने के बाद विधायकों की खरीद-फरोख्त शुरू हुई ही थी कि इंका के कटु आलोचक रह चुके पूर्व मुख्यमंत्री लिंगडोह ने घोषणा कर दी कि उनकी पार्टी एचपीयू 'स्थायी' सरकार बनाने के लिए इंका से हाथ मिलाएगी. एचपीयू की 19 सीटें हैं. उन्होंने कहा, "मेरी रुचि मुख्यमंत्री बनने में नहीं है." इस प्रस्ताव से इंका के नेता उछल पड़े और राज्यपाल भीष्म नारायण सिंह के पास भागे-भागे गए. राज्यपाल ने इंका के नेतृत्व वाले गठजोड़ को सरकार बनाने के लिए न्यौतने में एकदम वक्त जाया नहीं किया.

मुस्कराते हुए संगमा राजभवन से बाहर निकले. तभी एचपीयू के महासचिव स्टानलिंगदन डेविड खोंगवीर हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (एचएसपीडीपी) और पब्लिक डिमांड्स इंप्लीमेंटेशन कंवेंशन (पीडीआइसी) के नेताओं के साथ बहुमत का दावा करने राजभवन जा पहुंचे.

लेकिन नए दावेदारों ने अपने समर्थकों के नामों और नेता के बारे में साफ-साफ कुछ नहीं कहा. सिंह ने उनके दावे खारिज कर दिए और संगमा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर डाला. उनका कहना था, "मुझे विश्वास है कि संगमा का गठजोड़ स्थायी सरकार बनाने में सक्षम रहेगा." लेकिन उनके इस तर्क से खोंगवीर सहमत नहीं थे. उनका दावा है, "सिर्फ लिंगडोह ही एचपीयू नहीं हैं. उनके फैसले से पार्टी के ज्यादातर लोग सहमत नहीं हैं." बाद में खोंगवीर ने अन्य निर्दलीय और क्षेत्रीय दलों के विधायकों के हस्ताक्षर इकट्ठे करके दावा किया कि उनके गठजोड़ में संगमा के गठजोड़ से अधिक विधायक शामिल हैं.

यह भी संयोग ही है कि इंका एचपीयू के साथ हाथ मिलाने को तुरत-फुरत तैयार हो गई. ये दोनों पार्टियां एक-दूसरे की खुल्लम-खुल्ला विरोधी हैं. लेकिन संगमा को इस पार्टी का समर्थन लेने में कुछ गलत नहीं लगता क्योंकि उनकी नजर में लिंगडोह राष्ट्रवादी हैं. एचपीयू में अब टूट निश्चितप्राय है और संगमा मंत्रिमंडल का भाग्य इस पर निर्भर होगा कि लिंगडोह कितने विधायकों को फोड़कर साथ ला सकते हैं.

संगमा को यह मानकर भी चलना है कि उनकी पार्टी को विभिन्न क्षेत्रीय पार्टियों के वोट बंट जाने से फायदा मिला है लेकिन इसकी वास्तविक लोकप्रियता काफी कम है. चुनाव में इंका को कुल पड़े मतों का 25 फीसदी ही मिल पाया है.

एक महत्वपूर्ण सीट पर सिक्का उछालकर हुए फैसले में भी इंका को एक सीट गंवानी पड़ी. इंका के बुरी तरह हारने वाले प्रमुख नेताओं में ग्रोसवेल मीलीएंगप, स्वास्थ्यमंत्री डॉ. पी.ए. खोंगलम, शिक्षामंत्री ओरीस लिंगडोह और परिवहनमंत्री रोवेल लिंगडोह भी शामिल हैं.

विपक्षी खेमे में यह साफ था कि अगर उनमें एका होता तो कहानी कुछ और ही होती. 11 सीटों पर विपक्ष को इंका से ज्यादा मत मिले लेकिन मतों के विभाजन से इंका

कई क्षेत्रीय पार्टियों के बीच मतों के बंटवारे से इंका फायदे में तो रही, फिर भी उसे 25 फीसदी मत ही मिल पाए

पैट्रीकार

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जीत गई. विपक्षी दलों को इससे भी काफी क्षति हुई कि कमोबेश सभी ने एक जैसी क्षेत्रीय मांगों को उछाला, जिससे मतदाताओं के लिए यह तय कर पाना मुश्किल हो गया कि पार्टियों में अंतर क्या है?

दूसरी तरफ यह भी एकदम साफ था कि विपक्षी दलों की इन कमजोरियों का फायदा इंका अधिक सफलतापूर्वक क्यों नहीं उठा सकी. पिछले साल मार्च में खासी छात्र संघ ने बहिरागत-विरोधी आंदोलन चलाकर राज्य प्रशासन को ठप कर दिया था. उस समय कैप्टन संगमा की सरकार बगलें झांकने लगी थी. इसका मुख्य कारण यही था कि छात्रों ने विदेशी-द्वेष, क्षेत्रीयता की उत्तेजना फैलाने वाली कई मांगें खड़ी कर दीं. तत्कालीन मुख्यमंत्री आदिवासियों की भावनाओं को ठेस पहुंचने के डर से नरम रुख अपनाए रहे. बल्कि आदिवासियों की उग्र भावनाओं का फायदा उठाने के लिए उन्होंने परमिट वाली मांग का सार्वजनिक रूप से समर्थन भी कर डाला.

इस रवैये के कारण हजारों नेपालियों को उजड़ना पड़ा (देखिए इंडिया टुडे, 15 फरवरी) और गैर-आदिवासियों का जीवन असुरक्षित बन गया. स्कूल और कॉलेज बंद हो गए और इस महीने के अंत तक ही उनके खुलने की उम्मीद है.

शिलंग में जातीय तनाव के अलावा गारो पहाड़ी जिले के मुख्यालय तूरा में सांप्रदायिक दंगे भी भड़क उठे. दोनों संगमा गारो से हैं और इसे इंका का परंपरागत गढ़ माना जाता है. दंगों के साथ सरकार की विश्वसनीयता भी खत्म हो गई. इस तरह इंका का गढ़ ढह गया. यहां 24 सीटों में से उसे सिर्फ 7 सीटें मिलीं जबकि उन्हें 22 सीटों पर जीतने की उम्मीद थी. कैप्टन संगमा ने स्वीकार किया, "मनोवैज्ञानिक घावों को भरना शायद हमारे लिए संभव नहीं था."

अब पुरनो संगमा को विरासत में सिर्फ अविश्वसनीयता ही नहीं मिली बल्कि गारो और खासी जैंतिया जातियों के बीच अलगाव भी बढ़ रहा है. परंपरा से भी इन जातियों में कभी नजदीकी रिश्ते नहीं रहे. संगमा गारो जाति के हैं और खासी इलाकों में अब ऐसे पर्चे भी बंटने लगे हैं जिनमें गारो जाति द्वारा खासियों पर अपनी राजनैतिक प्रभुता कायम रखने का आरोप मढ़ा गया है. चुनाव के बाद इंका विधायक दल की बैठक में पूर्व गृहमंत्री पी.रीप्पल ख्यांदिआह ने कहा कि पार्टी को खासी पहाड़ी इलाकों से ही ज्यादा सीटें मिली हैं इसलिए यह स्वाभाविक उम्मीद बंधती है कि अगला मुख्यमंत्री कोई खासी ही होना चाहिए. यह कहकर वे खासियों की आम भावना को ही अभिव्यक्ति दे रहे थे.

उधर राजीव गांधी ने विधानसभा चुनावों से पहले ही पुरनो संगमा को तूरा से चुनाव लड़ने का निर्देश देकर अपना फैसला सुना दिया था. तीन दशकों से विधायक और 16 साल तक मुख्यमंत्री रह चुके कैप्टन संगमा दरकिनार कर दिए गए. इसलिए अपने जातिभाई और शिष्य के नेतृत्व वाली नई सरकार के प्रति उनका रुख पार्टी के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा.

लेकिन दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विपक्षी नेताओं तक का मानना है कि पुरनो संगमा इस स्थान के लायक व्यक्ति हैं. काम करवा लेने की क्षमता की उनकी प्रतिष्ठा अब कहावत का रूप ले चुकी है. केंद्र के सत्ता के गलियारे में आने के बहुत पहले से ही वे अपने क्षेत्र और गारो पहाड़ी इलाके के लिए बहुत कुछ करते रहे हैं.

अब देखना है कि राज्य में अस्थिरता की स्थिति को पलटने के लिए पुरनो संगमा क्या रणनीति अपनाएंगे? पर इससे पहले उन्हें आने वाले विधानसभा सत्र में विपक्ष की एक जोरदार चुनौती का सामना करना होगा.

—रमेश मेनन और कमलजीत रतन

बातचीत

'मुझे चुनौती मंजूर है'

कई वर्षों से 40 वर्षीय पुरनो अगिटोक संगमा मेघालय राजनीति के उदीयमान सितारे हैं. नई दिल्ली में केंद्रीय राज्य श्रममंत्री के रूप में धाक जमाने के बाद प्रधानमंत्री ने उन्हें मेघालय में इंका की प्रतिष्ठा बहाल करने के लिए चुना. मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने के बाद ही उन्होंने वरिष्ठ संवाददाता ***रमेश मेनन और कमलजीत रतन*** *से बात की. उसके अंश:*

● ***इंका इस तरह असफल क्यों रही?***

पिछले छह महीनों से चले आ रहे सांप्रदायिक हिंसा और जातीय दंगे ही इसके लिए जिम्मेवार हैं.

● ***केंद्रीय राज्यमंत्री से राज्य का मुख्यमंत्री बनने पर आपकी राय?***

मुख्यमंत्री का पद अधिक चुनौती भरा है. केंद्र में मंत्री के अधीन केवल एक ही विभाग होता है. मुख्यमंत्री को बहुत कूटनीति से काम लेना पड़ता है.

● ***आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी?***

पहले कानून और व्यवस्था की स्थापना, उसके बाद राज्य का विकास.

● ***वनवासी और गैर-वनवासियों के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए आपकी योजनाएं?***

हमें लोगों को विश्वास दिलाना होगा कि एक साथ रहकर ही वे उन्नति कर सकते हैं.

● ***क्या आप राज्यों में प्रवेश के लिए परमिट के पक्ष में हैं?***

मैं नहीं मानता कि वनवासियों की संस्कृति और अस्तित्व की रक्षा इससे की जा सकती है. इसके लिए मेरे पास दो उपाय हैं—जीवन स्तर ऊंचा उठाना और शिक्षित करना.

● ***आपकी सरकार कितनी टिकाऊ सिद्ध होगी?***

मैं महज नाम के लिए सरकार नहीं चलाना चाहता, हमें बाकी दलों का भी समर्थन है.

पुरनो संगमा: नई जिम्मेदारी

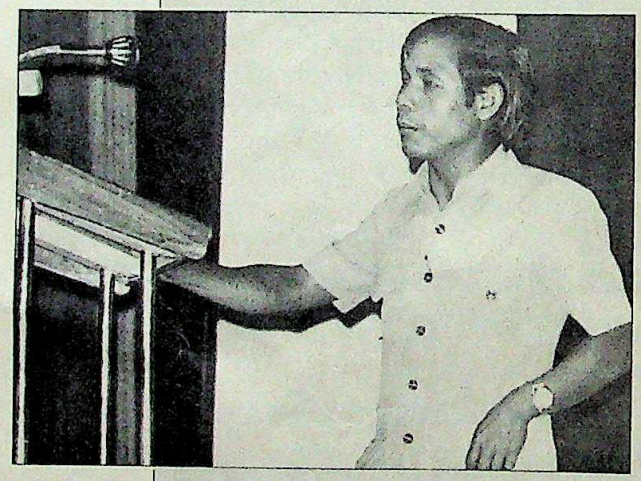

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ज़रा सोचिए आपने बिजली जाने से

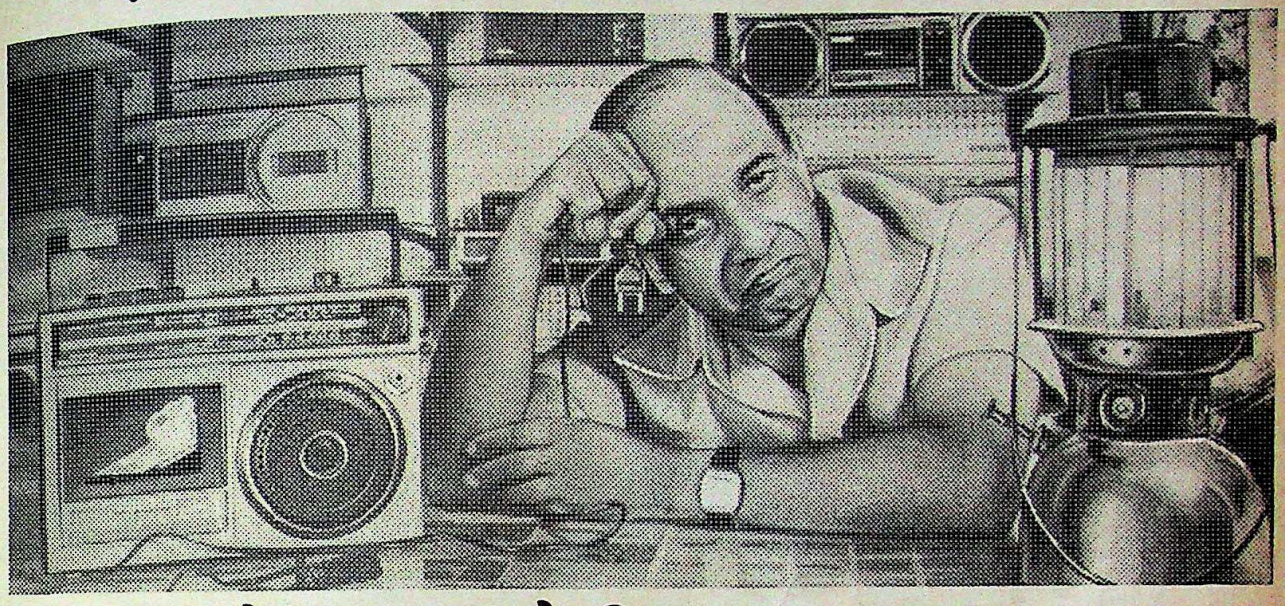

कितने ग्राहक खो दिए!

यह बहुत खराब लेकिन सच बात है कि अंधेरे में कोई खरीददारी नहीं करता। और यह भी सच है कि जब लोग खरीदेंगे नहीं तो आपकी बिक्री कैसे होगी। लेकिन बिक्री हो या न हो आपको खर्चे तो करने ही पड़ेंगे। यानि हर बार जब भी बिजली जाएगी, आपकी जेब कुछ और तंग हो जाएगी। लेकिन यह सब पुरानी बातें हैं।

चूंकि अब आपको रोज़-रोज़ की परेशानी से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाने का आसान सा समाधान ले आए हैं बिड़ला यामाहा, जिन्होंने भारत में पहली बार बनाए हैं विश्व-स्तर के जेनरेटर। भरोसेमंद और ईंधन बचाने वाले लिटिल जीनी पोर्टेबल जेनरेटर — दो स्ट्रोक और चार स्ट्रोक वाले — जो बिजली बंद होने पर भी आपको देते हैं बिजली। चलाने में एकदम आसान, एक झटके में हो जाएं स्टार्ट!

यही हैं वे एकमात्र पोर्टेबल जेनरेटर जो खासतौर पर भारतीय परिस्थितियों में इस्तेमाल के लिए बने हैं। गरजती बारिश हो या चमकती धूप, जितना जी चाहे बेदर्दी से इस्तेमाल कीजिए, ये चुपचाप चलते रहेंगे। और अगर कभी कुछ खराबी आ भी जाए — जिसका मौका शायद ही कभी आए — तो जापान के यामाहा से खासतौर पर प्रशिक्षित हमारे सर्विस इंजीनियर उसे ठीक कर देंगे — चाहे आप कहीं भी हों — 24 घंटे के भीतर।

इसका मतलब यह हुआ कि फिर आपको कभी बिजली की कटौती का कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। इतने सारे उन समझदार लोगों की ही तरह जो अपना लिटिल जीनी पोर्टेबल जेनरेटर खरीद चुके हैं।

अपना लिटिल जीनी पोर्टेबल जेनरेटर आज ही खरीदिए और आज ही से दिन-दूना रात-चौगना मुनाफा कमाइए।

कृपया मुझे भेज दीजिए

☐ मुफ्त सूचना पुस्तिका ☐ आर्डर फार्म

मुझे चाहिए लिटिल जीनी अपने

☐ घर ☐ दफ्तर ☐ वर्कशॉप ☐ शोरूम के लिए

नाम _____

व्यवसाय _____

पता _____

_____

31

मार्केटिंग डिवीजन

बिड़ला यामाहा लिमिटेड

ए-7, साउथ एक्स्टेंशन भाग-1, रिंग रोड,
नई दिल्ली-110 049

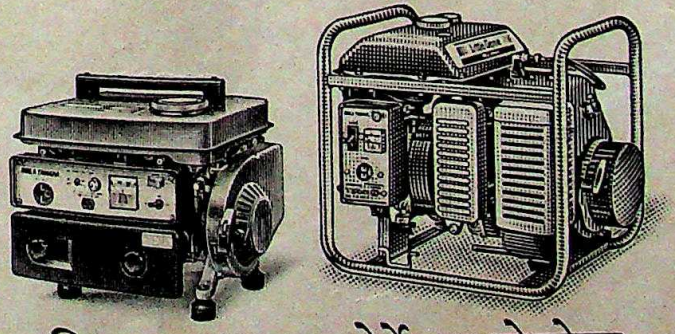

बिड़ला यामाहा पोर्टेबल जेनरेटर
खासतौर पर भारतीय परिस्थितियों के लिए बने

Sista's BYL-241/88 HN A

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इंका मुख्यमंत्री

दांव पर लगे मोहरे

राज्यों में बड़े पैमाने पर फेरबदल की आशंका

अधिकांश इंका मुख्यमंत्रियों के मन में प्रधानमंत्री राजीव गांधी से हुई मुलाकातों की सुखद यादें अभी बाकी हैं. हाल तक तो यही लगता रहा है. आखिर राजीव ही वे व्यक्ति हैं जो धैर्यपूर्वक उनकी बात सुनते आए हैं. लेकिन अब इस साल की शुरुआत से ही उन्होंने भी मानो चाबुक फटकारना शुरू कर दिया है.

अचानक बहुत से मुख्यमंत्रियों ने पाया कि राजीव से उनकी मुलाकात के सभी रास्ते रोक दिए गए हैं और जो किसी तरह मिलने में सफल हो भी पाए, बाद में इसी बात पर मलाल करते रहे कि उन्हें नहीं मिलना चाहिए था. राजीव ने बड़ी बेरुखी के साथ उनसे कहा कि या तो वे अपना रास्ता बदल लें या फिर इस्तीफा दे दें. इस साल महाराष्ट्र और ओडीसा के मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण और जानकीबल्लभ पटनायक राजधानी की अपनी पहली यात्रा के दौरान राजीव से मिले बिना ही वापस लौट गए. राजस्थान के मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर मिलने में तभी कामयाब हो पाए जब उनके प्रतिद्वंद्वी जगन्नाथ पहाड़िया ने उन्हें साउथ ब्लॉक पहुंचने के लिए मजबूर कर दिया. और गनीमत है कि उत्तर प्रदेश के लड़खड़ाते मुख्यमंत्री बीरबहादुर सिंह मुलाकात का समय पाने में करीब आधा दर्जन नाकामयाब कोशिशों के बाद ही कहीं कामयाब हो पाए.

एक लंबे अर्से से नई दिल्ली ने मुख्यमंत्रियों का ऐसा जमावड़ा नहीं देखा था. हालांकि कहने को तो वे अपने योजना प्रारूपों की चर्चा करने के लिए योजना आयोग में आए थे पर उसके बाद कई दिनों तक वे राजीव से मुलाकात की आशा में दिल्ली में ही लटके रहे. ऐसे ही एक परेशान नेता ने तो बुलावे के इंतजार में 18 घंटे अपने कमरे में ही गुजार दिए. लेकिन बुलावा था कि अंत तक नहीं आया. एक मुख्यमंत्री के साथ आए मंत्री का कहना था, "प्रधानमंत्री कार्यालय ने उनसे जो व्यवहार किया वह चपरासियों से किए जाने वाले व्यवहार से कोई बेहतर नहीं कहा जा सकता है. मुख्यमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार कहां का न्याय है भला?"

लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय इस संबंध में अपना ही तर्क प्रस्तुत करता है. राजीव के एक सलाहकार के अनुसार अधिकतर मुलाकाती तो बिना बुलाए ही आ टपकते हैं. और कम महत्वपूर्ण मामलों तक में भी वे प्रधानमंत्री को उलझाए रखते हैं.

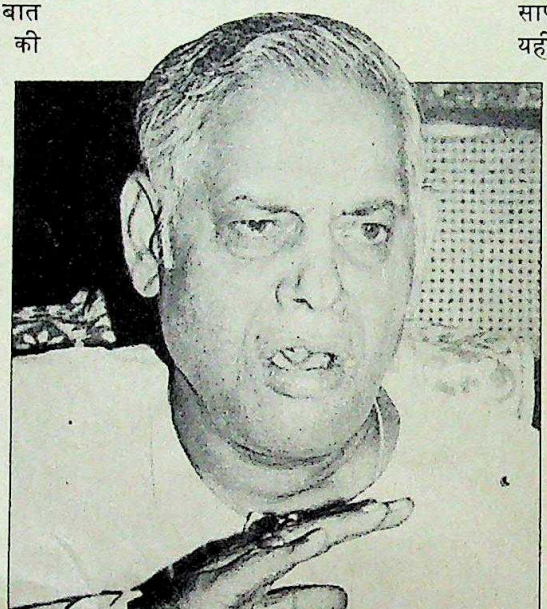

दुबे का जाना अब तय माना जा रहा है. अरसे से उन पर ऐसी सरकार चलाने के आरोप लगाए जा रहे हैं जो कुछ नहीं करती

राजीव ने अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों और इंका महासमिति के पदाधिकारियों के साथ पार्टी और सरकार की छवि निखारने के लिए जब विचार-विमर्श प्रारंभ किया, राज्यों के ये नेता भी दिल्ली आ धमके. प्रधानमंत्री के लक्षद्वीप में छुट्टियां मनाकर लौटने के तुरंत बाद प्रारंभ हुई इस प्रक्रिया ने राजस्थान के मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी से इस्तीफा दिलवा दिया. राजीव का 60 कांग्रेसी सांसदों, सभी प्रदेश इंका कांग्रेस समितियों के महासचिवों और आधा दर्जन कांग्रेस समितियों से मिलना इसी कवायद का एक हिस्सा था. इंका के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार यह फेरबदल राज्यों, केंद्र और अफसरशाही सभी स्तरों पर एक साथ होने जा रहा है.

स्पष्ट है कि राजीव के जहन पर यह दबाव काम कर रहा है कि आम चुनाव अब अधिक दूर नहीं हैं. और तब तक पार्टी की साफ छवि लोगों में बनानी है. आम राय भी यही थी कि राज्यों से ही फेरबदल प्रारंभ किया जाए. उत्तर भारत क्योंकि सबसे संगीन चुनावी इलाका है इसलिए जोशी के जाने के बाद बिहार के बिंदेश्वरी दुबे की समीक्षा किए जाने पर किसी को अचंभा नहीं हुआ.

पिछले तीन साल से इस बुजुर्ग ट्रेड यूनियन नेता पर आरोप लगते रहे हैं कि वे काम न करने वाली सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं. पिछले पखवाड़े जब उनका पत्ता कटना लगभग तय लग रहा था, तब उन्होंने अपने सहयोगियों, कनिष्ठ अधिकारियों और समर्थकों को जबरदस्ती ओढ़ी गई मुस्कान के साथ निर्देश दिया कि वे 'अफवाहों' पर बिलकुल भी ध्यान न दें और पहले की तरह ही अपना-अपना कामकाज करते रहें.

लेकिन नई दिल्ली के सामने एक दिक्कत है. दुबे की जगह न केवल कार्यकुशल और राजनैतिक पैंतरेबाज आना चाहिए बल्कि वह बिहार की जटिल जातीय राजनीति की बिसात में भी फिट बैठता हो. वैसे इस पद के चाहने वालों में बहुत से हैं और उनके पास अपने समर्थन में बहुत-सी दलीलें भी हैं. कुछ लोगों का तर्क है कि दुबे चूंकि ब्राह्मण हैं इसलिए उनकी जगह किसी ब्राह्मण को ही लेनी चाहिए. इसी तर्क के साथ बिहार विधानसभा के अध्यक्ष शिवचंद्र झा, वरिष्ठ नेता और सांसद भागवत झा आजाद और विवादास्पद पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री कमलकांत तिवारी के नाम भी लगातार उछाले जा रहे हैं.

हालांकि असम के राज्यपाल भीष्मनारायण सिंह को पार्टी आलाकमान का समर्थन मिलता नजर आता है लेकिन परेशानी यहां भी है. बीरबहादुर सिंह की तरह वे भी राजपूत हैं. इसलिए यह घटिया राजनीति ही प्रतीत होगी कि देश के दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्यों में दो नेता एक ही

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जाति के बैठा दिए जाएं. एक समय तो सेवादल के प्रमुख तारिक अनवर का नाम भी चर्चा में था. उनके समर्थन में तर्क था कि वे जातीय राजनीति को तटस्थ कर देंगे और साथ ही साथ बहुत सारे मुस्लिमों का दिल भी जीतने में कामयाब रहेंगे.

मगर इस सबके बावजूद पद के सर्वाधिक सशक्त दावेदार पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र ने अपने पत्ते सही ढंग से खेले. इस बात को समझते हुए कि कम चर्चित व्यक्ति की सर्वाधिक संभावनाएं होती हैं उन्होंने सुनिश्चित कर दिया कि पटना के समाचार-पत्र उन्हें प्रत्याशी के रूप में न दिखाएं. लेकिन राष्ट्रीय दैनिक जल्द ही उनकी संभावनाओं से भर गए. सभी ने लिखा कि वे बिहार के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं.

जगन्नाथ मिश्र ने पार्टी हाकिमों को न केवल नाम सुझाने से इनकार कर दिया बल्कि अध्यक्ष झा द्वारा लोगदल-ब के कर्पूरी ठाकुर को विपक्ष के नेता पद से अपमानजनक तरीके से हटाए जाने की शिकायत भी की. उन्होंने कहा कि इससे पिछड़ा वर्ग इंका के विरुद्ध हो जाएगा. मिश्र ने राजीव से शायद यह भी कहा कि केवल जातीय आधार पर ही गौर नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसके लिए किसी प्रत्याशी की प्रशासनिक क्षमता, व्यक्तिगत प्रभाव और आम समर्थन का भी आकलन होना चाहिए. यह बात अन्य सभी के दावों को ध्वस्त करने के नजरिये से कही गई थी. इसके पीछे उनकी अपनी महत्वाकांक्षा काम करती दिखाई देती थी. इस बीच जगन्नाथ मिश्र के प्रमुख प्रतिद्वंद्वी और पार्टी कोषाध्यक्ष सीताराम केसरी तो कम-से-कम आगामी मार्च में होने वाले राज्यसभा चुनावों तक बिंदेश्वरी दुबे के बचाव के लिए जुट जाएंगे. इससे मिश्र की योजनाओं पर पानी फिर गया है. वे प्रत्याशियों के रूप में नए-नए नाम उछालने में लगे हुए हैं ताकि भ्रम की स्थिति को बढ़ावा मिले और दुबे को इसका तात्कालिक फायदा अवश्य ही मिलता रहे.

पार्टी के एक नेता कहते हैं, "यदि आलाकमान दुबे के निकम्मेपन के बावजूद उन्हें अभी तक हटा नहीं पाया है तो कारण यह है कि वह भी दुविधा में है. दुबे और आलाकमान दोनों ही बिहार की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार हैं. इसका पता तो उन्हें अगले चुनाव में ही लगेगा."

राज्य की वार्षिक योजना के लिए विचार-विमर्श के संबंध में राजीव द्वारा दुबे को बुलाते ही राजनैतिक गतिविधियों ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी. पटना में जगन्नाथ मिश्र का निवास 2, सरकुलर रोड पर भी लगभग उसी समय फोन की घंटी घनघना उठी. फोन करने वाला कोई और नहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय का एक अधिकारी था जिसने मिश्र को, जो उस समय उत्तरी बिहार के दौरे पर थे, तुरंत नई दिल्ली बुलावे का संदेश दिया. इस बुलावे से अचंभित मिश्र दो दिन बाद रवाना हुए और उन्हें 45 मिनट तक दिल खोलकर राजीव के साथ बातचीत का मौका दिया गया. मिश्र के अचंभित होने की बात समझ में आती है. 1983 में

चव्हाण के बच जाने की काफी उम्मीद है. वे राजीव को समझाने में कामयाब रहे हैं कि उनकी नाकामी पार्टी में अनुशासनहीनता के कारण रही

मुख्यमंत्री पद जोर-जबरदस्ती छुड़वाए जाने के बाद पार्टी आलाकमान द्वारा उनकी लगातार उपेक्षा की जाती रही है. उनकी अभी तक कोई पूछ ही नहीं थी.

जहां एक ओर मिश्र प्रसन्नचित पटना लौटे, वहीं दुबे इस बात पर लगातार जोर देते रहे कि वे अभी हटाए जाने वाले नहीं हैं. वे जोर देकर कहते रहे, "प्रधानमंत्री ने न तो मुझसे राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की बात की और न ही मुझसे कोई वैकल्पिक नाम सुझाने को कहा." दिलचस्प बात यह है कि हरिदेव जोशी भी राजस्थान के मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के समय तक इसी तरह की भावनाएं व्यक्त करते रहे थे.

बहादुरी भरे बयानों को छोड़ दें तो योजना आयोग के लिए बिंदेश्वरी दुबे की नई दिल्ली यात्रा ने उनकी असलियत खोलकर रख दी. दिल्ली में वे जिन नेताओं से मिल पाए वे इतने सशक्त नहीं थे कि इस राजनैतिक ज्वार-भाटे को मोड़ सकें. इनमें सीताराम केसरी भी शामिल हैं जिन्होंने एक माह पहले ही राज्यसभा का टिकट मिल जाने की उम्मीद में सार्वजनिक रूप से दुबे के पैर छू लिए थे. जिन अन्य लोगों के दरवाजे उन्होंने खटखटाए उनमें इंका महासचिव नरेशचंद्र चतुर्वेदी, जो बिहार के मामलों के प्रभारी हैं और ग्राम्य विकास राज्यमंत्री रामानंद यादव शामिल हैं. दोनों ही पार्टी में कोई खास अहमियत नहीं रखते. रक्षामंत्री कृष्णचंद्र पंत और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता उमाशंकर दीक्षित सरीखे अन्य केंद्रीय नेता, जो सहायक साबित हो सकते थे, उनकी तरफ से भी उन्हें कोई प्रोत्साहन नहीं मिला. डूबते हुए आदमी की तरह व्यवहार करते हुए दुबे ने उन 100 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को बिहार भवन में नाश्ते पर आमंत्रित किया जिन्हें राज्य में पार्टी के आम जागरूकता अभियान में पर्यवेक्षक के रूप में तैनात किया गया है. लेकिन इंका महासमिति के संयुक्त सचिव और कार्यक्रम संयोजक जर्नादन द्विवेदी ने अडंगा खड़ा कर दिया. इसलिए मुश्किल से एक दर्जन लोग ही वहां पहुंच पाए.

जब उनके राजनैतिक परामर्शदाताओं ने उन्हें धोखा दिया तो दुबे ने अवतारी लोगों के दरवाजे खटखटाए. वह देवरहवा बाबा का आशीर्वाद पाने वृंदावन भी गए जिनके वह अनन्य अनुयायी हैं. अपनी गद्दी दांव पर लगी होने के कारण वह दिल्ली के दो और अवतारी पुरुषों के दर्शन करने भी गए.

यह पहली बार नहीं है कि जब दुबे को हटाए जाने पर विचार किया जा रहा है. इंका के हाकिम पिछले कुछ समय से राज्य में पार्टी की गतिविधियों और राज्य सरकार दोनों से असंतुष्ट थे. लेकिन एक-न-एक कारण से प्रयास स्थगित किए जाते रहे . उदाहरण के लिए, एक साल पहले उन्हें हटाने का एक प्रयास तब समाप्त हुआ जब दुबे ने सांसदों के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात राजीव से करवाई और उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

की गतिविधियां संतोषजनक चल रही हैं. बाद में इन्हीं सांसदों ने राजीव से कहा, "हमारे द्वारा सरकार की छवि सुधारे जाने के भरसक प्रयासों के बाद भी सरकार कार्य करने में असफल रही है."

शिकायतें बढ़ती गईं और जगन्नाथ मिश्र दुबे की सरकार की आलोचना और कमियां गिनाते हुए जोरदार ढंग से लगातार अपना 'जन-जागरण अभियान' चलाते रहे. दो माह पहले वे राजीव गांधी से मिले और दुबे के खिलाफ इस आशय का एक आरोपपत्र दिया कि किस तरह सरकार 'जनता की परेशानियों' के प्रति 'निष्ठुर और अनभिज्ञ' हो गई है. राजीव की पहल पर हुई छानबीन में ये आरोप सरकार के प्रगति के दावों के बावजूद बहुत हद तक सही पाए गए.

बात केवल इतनी ही नहीं थी. पिछले साल दिसंबर में बिहार के कुछ सांसदों से एक गुट गठित कर राज्य सरकार की कार्य-कुशलता पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया. लेकिन ऐसा लगता है कि बिहार में बाढ़ राहत कार्यों में घपले-बाजी संबंधी जांच कर रहे सड़क परिवहनमंत्री राजेश पायलट की रिपोर्ट ने राजीव का विचार बदल दिया वे राज्य के बाढ़ राहत और पुनर्वास कार्यों के समन्वयक भी हैं. उन्होंने पाया कि सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी नहीं किया है. परेशानी के कई कारण हैं—बिहार के 39 जिलों में से 30 को शताब्दी की भीषणतम बाढ़ का सामना करना पड़ा है. ये जिले 324 सदस्यों की विधानसभा में 146 विधायक भेजते हैं और राज्य के 54 सांसदों में 20 तो इन्हीं क्षेत्रों से चुनकर आते हैं.

अगर गाज दुबे पर गिरी तो इसकी वजह उनकी अकुशलता होगी, पर महाराष्ट्र में चव्हाण का मामला पूरी तरह अलग है. उनके कामों की समीक्षा तब हुई जब दो पूर्व मुख्यमंत्रियों शरद पवार और वसंतराव पाटील ने इन पर हल्ला बोला. महाराष्ट्र ने लोकसभा में 48 सांसद भेजे हैं इसलिए उसे इंका के लिए बहुत सुरक्षित इलाका समझा जाता है. वहां राजीव किसी फेरबदल के मूड में भी नहीं लगते हैं.

चव्हाण के खिलाफ मुख्य आरोप हैं:

- ► वे पार्टी विधायकों और सांसदों को नजरअंदाज करते हैं;
- ► शिवसेना कांग्रेस-इ की कीमत पर अपना आधार बढ़ाए जा रही है;
- ► मंत्रिमंडल में बहुत ही अधिक मराठा भर गए हैं जिससे दूसरी जातियों के नेताओं की जड़ें खुद रही हैं;
- ► राज्य असरदार तरीके से सूखे से निबट पाने में नाकाम रहा है.

इसी बीच दिल्ली में चव्हाण के खिलाफ जो लगातार गुटबाजी चल रही है उसके रहते 18 महीने से वे अपने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पाए हैं. इसीसे उनके हटाए जाने की अटकलें भी लगने लगीं. पर फिलहाल चव्हाण राजीव को यह समझाने में कामयाब हो गए हैं कि उनकी नाकामियों की वजह पार्टी में फैल रही अनुशासनहीनता है. एक चव्हाण समर्थक विधायक का कहना है, "उनसे कुछ कर पाने की उम्मीद भी कैसे की जा सकती है जब राज्य के नेता केंद्र की कुछ ताकतों से मिलीभगत करके उनकी कोशिशों की ही जड़ें खोदने पर तुले हों."

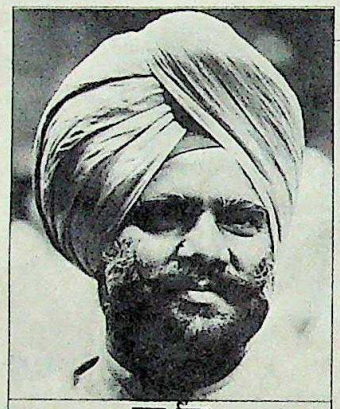
बूटा सिंह

केदारनाथ सिंह

बूटा सिंह का कहना है कि सब कुछ ठीकठाक चल रहा है. राज्य सरकार में फेरबदल की योजना मंजूर कराने के लिए वे जल्दी ही प्रधानमंत्री से मिलेंगे

राजीव मानते हैं कि चव्हाण पार्टी के उन चंद तजुर्बेकार नेताओं में हैं जिनकी छवि साफ-सुथरी है. और चव्हाण इसी वजह से बच गए हैं. इससे भी बड़ी बात यह है कि वे गुटबाजी से भी दूर हैं. इसके बाद ही चव्हाण मंत्रिमंडल से विवादास्पद मंत्रियों को निकाल बाहर करने और उनकी जगह अच्छी साख वाले लोगों को भरने का मामला आता है.

राजीव ने यह मामला गृहमंत्री बूटा सिंह और इंका महासचिव केदारनाथ सिंह को सौंप दिया है. वे चव्हाण से मिलकर नए मंत्रियों की सूची बनाएंगे. उन्होंने चव्हाण से कहा है कि वे राज्यमंत्री चंद्रिका केनिया और श्रीकांत जिचकार के खिलाफ आरोपों की जांच करें. साथ ही उन 16 नामों की सूची तैयार करें जिस पर राजीव से मशविरा किया जा सके. पर चव्हाण ने कह दिया है कि वे इन मंत्रियों को तब तक नहीं निकालेंगे जब तक उन पर लगे आरोप साबित नहीं हो जाते.

दो दिन पहले चव्हाण राजीव से दो बार मिले थे. चव्हाण ने साफ-साफ कह दिया था कि वे तब तक कुछ बेहतर नहीं कर सकेंगे जब तक उन्हें खुली छूट नहीं दी जाती. वे कहते भी हैं, "अगर मुझे ही सरकार चलानी है तो मैं उन्हीं लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करूंगा जो मेरे विश्वासपात्र हैं, पार्टी के वफादार हैं और आम जनता में जिनकी छवि साफ-सुथरी है." वे बूटा सिंह से भी मिले थे. इस मुलाकात के बाद उन्होंने संभावित मंत्रियों की एक और सूची तैयार की थी. गृहमंत्री और इंका महासचिव से मिल-बैठकर कोई फैसला हो पाता इससे पहले ही चव्हाण लौट गए. इसकी वजह सिर्फ यह थी कि दोनों ही उन्हें मुलाकात का समय नहीं दे सके. बंबई के लिए उड़ान भरने से पहले चव्हाण ने कहा, "जब उनके पास समय होगा, मैं तभी आऊंगा." उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें बंबई जल्दी से जल्दी लौटना है क्योंकि वहां सरकारी कर्मचारी हड़ताल करने की धमकी दे रहे हैं.

बूटा सिंह और केदारनाथ सिंह दोनों ने ही इस बात से इनकार किया है कि उनके पास चव्हाण जैसे व्यक्ति से मिलने का समय नहीं था. बूटा सिंह का कहना है, "महाराष्ट्र में हड़ताल की वजह से मुख्यमंत्री जल्दी अपने राज्य में लौटना चाहते थे. सब कुछ ठीकठाक है और हम जल्दी ही राज्य सरकार में फेरबदल की योजना मंजूर कराने के लिए प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं." पर जब तक यह होगा देश के एक खुशहाल राज्य महाराष्ट्र और एक सबसे गरीब राज्य बिहार के मुख्यमंत्रियों की किस्मत बेचारी अधर में ही लटकी रहेगी.

—प्रभु चावला और फरजंद अहमद

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सरकारिया आयोग

नपी तुली रपट

राष्ट्रीय बहस का नया न्यौता

कानून के अलावा न्यायमूर्ति राजिंदर सिंह सरकारिया का दूसरा शौक है नई-नई किस्मों के गुलाब उगाना. दिल्ली के मुनहरी बाग इलाके में अपने बंगले पर खिले बगीचे का गर्वीले अंदाज में मुआयना करते हुए वे कहते हैं, "सबसे अच्छे गुलाब तो कलमों से पैदा होते हैं, बशर्ते तना मजबूत हो. तना नरम हो तो बात नहीं बनती."

पिछले महीने केंद्र-राज्य संबंधों के बारे में उनकी अध्यक्षता वाले तीन सदस्यीय आयोग की 1579 पृष्ठों वाली रिपोर्ट सामने आई तब यह स्पष्ट हो गया कि संविधान के तहत केंद्र सरकार को अधिकार देने के विवादास्पद मुद्दे पर उन्होंने यही तर्क दिया है. वे कहते हैं, "निस्संदेह हमें मजबूत केंद्र की सख्त जरूरत है. इसके बिना तो मानो सब कुछ बिखर जाएगा."

इस आयोग का गठन पांच साल पहले तब किया गया था जब अधिक स्वायत्तता की मांग को लेकर अकाली दल ने आंदोलन छेड़ा हुआ था. आयोग को केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक अधिकारों के बंटवारे के सवाल का अध्ययन करने को कहा गया था. आयोग इस नतीजे पर पहुंचा है कि संविधान में कोई मूलभूत खामी नहीं है. लेकिन उसने राज्यों संबंधी मामलों के निबटारे के लिए अपनाए जाने वाले तौर-तरीकों की जमकर आलोचना की है.

इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि संविधान में किसी बड़े परिवर्तन का 'न तो कोई औचित्य है और न आवश्यकता' बल्कि असली कमी तो संविधान के पालन के मामले में रही है. आयोग ने खास तौर से हाल ही में सरकारों द्वारा अपनाए गए उन अक्खड़ तौर-तरीकों की आलोचना की है जिनके तहत महत्वपूर्ण जनतांत्रिक परंपराओं और नियमों को ताक पर रख दिया गया.

आयोग ने सुझाव दिया है कि प्रशासनिक मामलों के, खासकर उनके लिए जिन पर केंद्र और राज्यों के बीच अक्सर द्वंद्व हो जाता है, निबटारे के लिए एक अंतरसरकारी समिति बनाई जाए. इस समिति में प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी शामिल किया जाए.

आयोग की रिपोर्ट में राज्यपालों की नियुक्ति, उनकी भूमिका और अधिकारों के संबंध में भी बहुत कुछ कहा गया है. राज्यपालों की नियुक्ति में आयोग ने पहली शर्त यह रखी है कि सक्रिय राजनीतिकों को न नियुक्त किया जाए. इसके अलावा जब किसी राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार हो तब राज्यपाल केंद्रीय शासक दल से संबंधित व्यक्ति नहीं होना चाहिए.

आयोग के दूसरे सुझाव भी इसी तरह महत्वपूर्ण मगर गैर-चमत्कारिक और गैर-विवादास्पद हैं. लेकिन इसके बावजूद अधिकारिक तौर पर रिपोर्ट के जारी होने के पहले ही इस पर तरह-तरह के आक्षेप लगने लगे थे. जारी होने से पहले ही राष्ट्रीय अखबारों में रिपोर्ट के प्रमुख मुद्दों के छपने के बाद विपक्षी नेताओं ने इसकी आलोचना में ताबड़तोड़ बयान दे डाले. पंजाब में अकालियों ने भी इस रिपोर्ट को नामंजूर कर दिया हालांकि आयोग का गठन उन्हें ही खुश करने के लिए किया गया था.

पीआईबी

राजीव को रिपोर्ट देते हुए सरकारिया

रिपोर्ट के चुनिंदा अंश छपने से यह भ्रम फैला कि इसमें राज्यों की अधिक स्वायत्तता की मांग नकार दी गई है

इन प्रतिक्रियाओं से न्यायमूर्ति सरकारिया काफी क्षुब्ध हुए. उन्होंने कहा, "वे रिपोर्ट को पढ़े बगैर ही इसकी आलोचना कर रहे हैं. उन्होंने अखबार में छपी खबरों को ही पढ़ा है. रिपोर्ट पढ़ने के बाद उनके विचार बदल जाएंगे." न्यायमूर्ति सरकारिया को लगता है कि रिपोर्ट के चुनींदा अंशों के छापे जाने से लोगों में गलत धारणा बैठ गई कि आयोग ने यथास्थिति का समर्थन किया है और विकेंद्रीकरण की विपक्षी और क्षेत्रीय दलों की मांगों को नकार दिया है.

असल में, केंद्र ने इस संवेदनशील रिपोर्ट के साथ जो बरताव किया उसमें साजिश और विवाद का तत्व तो है ही. अखबारों में छपा कि आयोग ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव और अधिकारों के बंटवारे के लिए संविधान में भारी फेरबदल की मांग को नामंजूर कर दिया है. इन्हीं खबरों पर विपक्षी दलों ने गुस्से में बयान दे डाला और अखबारों ने आलोचनात्मक संपादकीय लिख डाले.

यह कहना मुश्किल है कि इस रिपोर्ट को पहले ही अखबार वालों को लीक करने के पीछे सरकार का कोई खास मकसद रहा होगा. लेकिन कुछ विपक्षी नेताओं का आरोप है कि ऐसा त्रिपुरा के मतदान में मार्क्सवादियों को पलटा देने के उद्देश्य से किया गया.

अब सरकार की तात्कालिक रणनीति 22 फरवरी को शुरू होने वाले संसद के बजट सत्र में विपक्ष द्वारा उठाए जाने वाले विशेषाधिकार हनन के मामले से निबटने की है. गृह मंत्रालय के अधिकारी चाहते हैं कि इस रिपोर्ट की प्रतियां देश भर में बांटी जाएं ताकि राजनैतिक और बुद्धिजीवी हलकों में इस पर बहस की शुरुआत हो. आम राय मिलने के बाद ही केंद्रीय मंत्रिमंडल इस पर गौर करेगा. यानी सरकारिया को अपने विचारों को कार्यरूप में परिवर्तित देखने के लिए लंबे समय तक इंतजार करना होगा.

—शेखर गुप्ता

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उत्तर प्रदेश

अद्भुत शक्ति प्रदर्शन

मेरठ शहर किसानों के कब्जे में आ गया लगता है

जनशक्ति का यह अद्भुत प्रदर्शन ही माना जाएगा. साल भर पहले वजूद में आए भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) ने जब 27 जनवरी को मेरठ के मंडल आयुक्त बी.के. देवन का दफ्तर घेरने का फैसला किया तो बीर बहादुर सिंह सरकार ने हड़तालियों को थका देने की अपनी पुरानी रणनीति आजमाई. लेकिन मुख्यमंत्री किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत के करिश्माई असर का अंदाज नहीं लगा सके और आंदोलन जोर पकड़ता गया. वामपंथी पार्टियों को छोड़ सारे विपक्षी दलों, दूसरे प्रदेशों के किसान संगठनों और मेरठ के लोगों ने टिकैत को समर्थन दिया.

पिछले साल तक कोई इस किसान नेता को जानता तक नहीं था. मटमैला कुर्ता-पायजामा पहनने वाला यह नेता जब मैदान में डटा तो उसने गांव और शहर दोनों के लोगों को जैसे चुंबक की तरह खींच लिया. उसने शुरू में ही कह दिया था, "यह दीवानों का खेल है, सिर्फ वही आएं जो अंतिम दम तक लड़ने की तैयारी रखते हों."

और लोग आए भी—ट्रैक्टर की ट्रॉलियों पर, ट्रकों की छतों पर, बैलगाडियों पर, मोटरसाइकिलों और कारों पर लदे-फंदे. बहुत तो पैदल ही आए. तकरीबन छह लाख की आबादी वाले मेरठ शहर ने लोगों का इतना बड़ा मेला कभी नहीं देखा था.

किसानों को थका देने की सरकार की योजना बेकार साबित हुई. धरना जारी रह सके इसके लिए हर रोज उत्तर प्रदेश के 20 जिलों से ट्रॉलियां भर-भरकर खाने-पीने का सामान पहुंचने लगा. प्रशासन ने 6,000 पुलिस वालों को तैनात किया था. पर फिर धीरे-धीरे वे बैरकों में लौट गए. बीमार पड़ने के बाद भी जो धरने से टस से मस होने को तैयार नहीं थे उनके इलाज के लिए डॉक्टरों की फौज तैनात कर दी गई. एक चिकित्सा अधिकारी के मुताबिक, "हम रोजाना 1,000 लोगों को दवाएं दे रहे हैं."

इस आंदोलन से वोटों के आंकड़ों का खेल कैसे बने या बिगड़ेगा यह तो अगला चुनाव ही बताएगा, लेकिन सुरक्षा लेखा प्रबंधक (सीडीए) के दफ्तर के आसपास इकट्ठे किसानों का आंकड़ा कुछ इस तरह गड़-बड़ाया— आंदोलन के पहले दस दिनों में 6 किसानों की मृत्यु हो गई. उनके पार्थिव शरीर मुख्य द्वार पर दर्शन के लिए रखे गए और सुबह से शाम तक हजारों लोग उन्हें अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते रहे.

टिकैत अपेक्षाकृत समृद्ध किसान हैं, इसलिए उन्हें अमीर किसानों का खासा समर्थन हासिल है. मेरठ में जमे किसानों के लिए नैनीताल से तीन समय का खाना आता

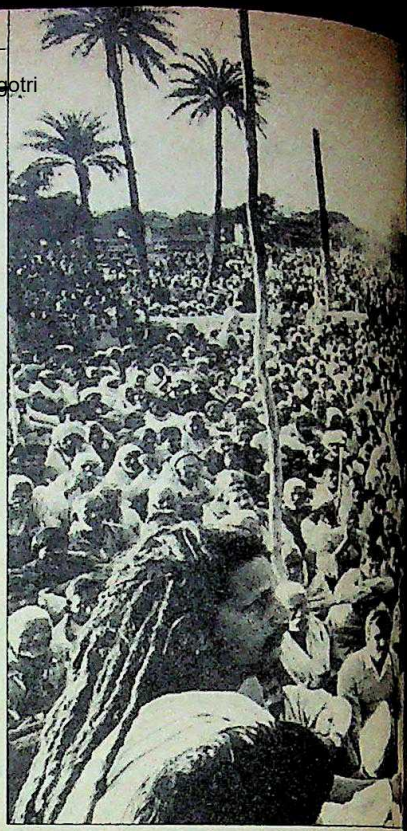

किसानों की सभा में टिकैत (दाएं) और दर्शन के लिए रखा आंदोलनकारी का शव

सभी फोटो: प्रमोद पुष्करण

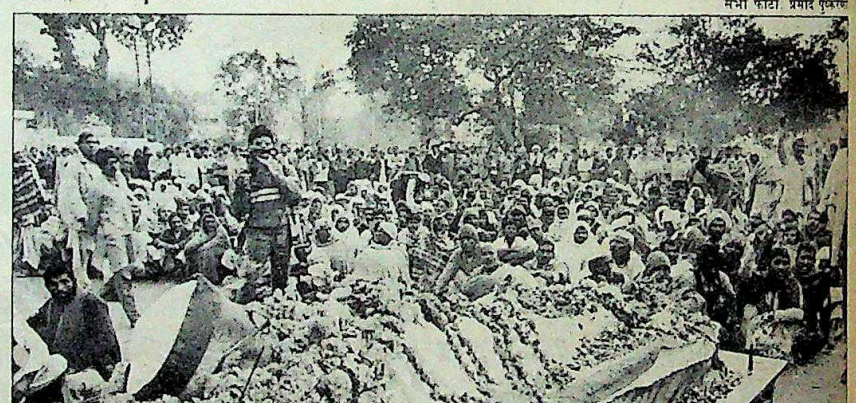

है—ट्रैक्टरों पर लदे हुए सेब, गाजर का हलवा आदि. पर कई छोटे किसान भी टिकैत के साथ हैं. टिकैत की लोकप्रियता ही इस आंदोलन को जिंदा रखे हुए है.

पिछले एक साल में ही टिकैत ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन पक्की की है, क्योंकि कोई दूसरा जाट नेता इस इलाके में सक्रिय नहीं है. चरण सिंह के निधन के बाद से इस इलाके में किसानों के बीच नेतृत्व शून्यता की स्थिति थी. टिकैत ने इस शून्य को काफी हद तक भरा है. उनके पीछे आज अंधभक्तों की बड़ी फौज खड़ी हो गई है.

कुछ महीने पहले हुए एक वाकये के कारण सरकार ने शुतुरमुर्गी रवैया अपना लिया है. 'भाकियू' ने टिकैत के गांव सिसौली की एक सभा में टिकैत के साथ भाषण करने के लिए बीर बहादुर सिंह को आमंत्रित किया था. यूनियन तभी से खार खाए बैठी थी जब 1986 में शामली में हुई पुलिस गोलीबारी में इसके तीन प्रदर्शनकारी मारे गए थे. सिसौली में यूनियन ने मुख्यमंत्री से इसी का बदला लिया. बीर बहादुर सिंह को बेइज्जत करने के लिए न तो किसी सरकारी अधिकारी को सभा में आने की इजाजत दी और न पार्टी के किसी पदाधिकारी को. वहां उन्हें एक लंबा-चौड़ा ज्ञापन दिया गया जो सर-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

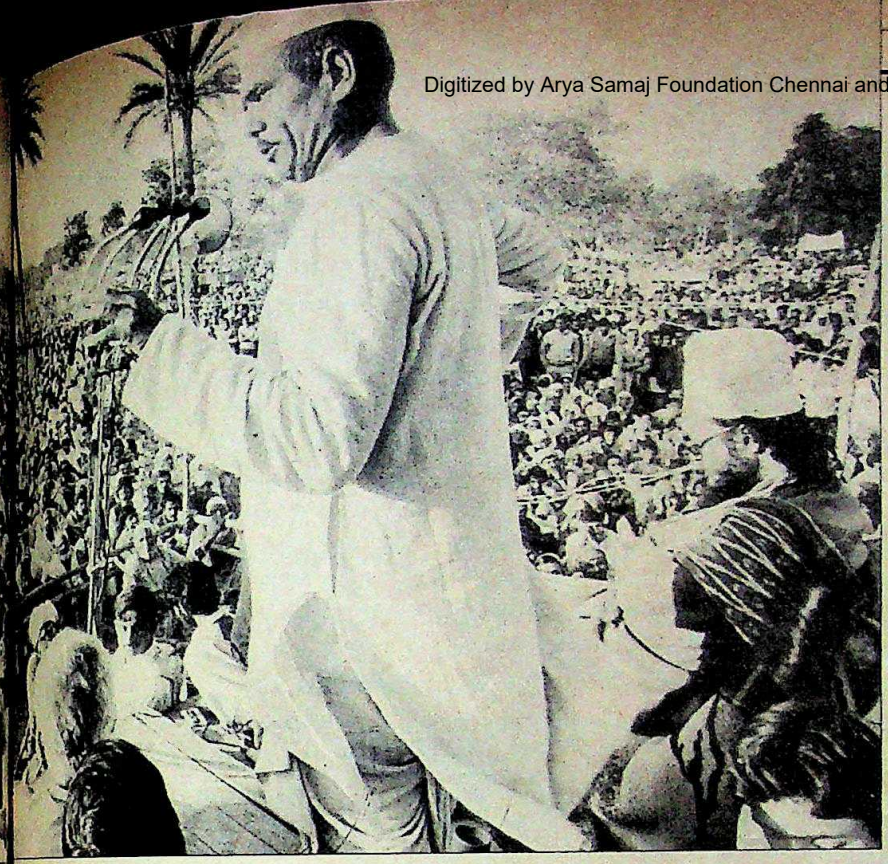

कारी फाइलों में दफन हो गया. अब मौजूदा आंदोलन शुरू करने से पहले किसान यूनियन ने यही मांगपत्र मेरठ के आयुक्त को भेजा. इसमें 35 मांगें थीं. जिलाधीश श्री शर्मा का कहना है, "27 दिसंबर तक हमें इन मांगों की कोई खबर नहीं मिली. राज्य सरकार ने भी हमें इस सिलसिले में कुछ नहीं बताया."

आंदोलन चला तो लखनऊ ने तरह-तरह के दांवपेच आजमाने शुरू किए. उसने स्थानीय अखबारों के संपादकों को ऐसे ब्यौरे भेजे जिसमें दावे किए गए कि सरकार ने किसानों के लिए क्या-क्या योजनाएं बनाई हैं. टिकैत को गिरफ्तार करने के लिए उनके मेरठ आने से एक दिन पहले 10 ट्रकों में पुलिस भेजी गई, पर गांव वालों की भीड़ के आगे इतनी पुलिस कुछ कर नहीं पाई. आंदोलन के तीसरे दिन आयुक्त ने स्थानीय स्तर पर 13 मांगें मान लीं, लेकिन किसानों की नजर कुछ ऊंची ही थी.

किसान यूनियन की अब तक जारी इक-लौती प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, "चीनी मिल मालिक शराब बनाने वालों को शीरा बेचते हैं और मुनाफा कमाते हैं. सरकार शराब बनाने वालों से राजस्व बटोरती है. किसानों को गन्ने की कीमत इसी के मुताबिक दी जानी चाहिए." आंदोलन अभी तक मुंहजबानी ही चल रहा है. यहां तक कि बीर बहादुर सिंह को भी शिकायत है कि उन्हें अभी तक कोई लिखित आश्वासन नहीं मिला. किसान यूनियन समय-समय पर अपनी मांगें बदलती भी रही है. बहरहाल, 27 दिसंबर को आयुक्त को दिए गए 35 सूत्री मांग पत्र की खास बातें ये हैं:

- सूखे की वजह से पिछले साल के कर्जे, किराए व बिजली के बिल माफ किए जाएं और बिजली की दरों में रियायत दी जाए.
- गन्ने की खरीद कीमत 27 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 35 रुपए की जाए.
- सरकारी नौकरियों में किसानों को आरक्षण, और किसानों को पेंशन दी जाए.
- कृषि मूल्य आयोग और स्थानीय विकास संगठनों में किसानों को प्रतिनिधित्व.
- सरकार जो जमीन अधिग्रहीत करे उसका बेहतर मुआवजा दिया जाए. और किसानों को जलावन के लिए पेड़ काटने का अधिकार दिया जाए.
- आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज फौजदारी मामले वापस लिए जाएं.

किसान यूनियन की विज्ञप्ति में कहा गया है कि कृषि पैदावारों की कीमत राष्ट्रीय मूल्य सूचकांक के आधार पर तय की जाए. फिर भी मुख्यमंत्री के नजदीकी बड़े अधिकारियों का कहना है कि, "वे मूलतः बड़ी जोतों के मालिक हैं. छोटे किसानों को साथ लेने के लिए उन्होंने अपनी ये मांगें शामिल की हैं."

कर्जे माफ करवाने की प्रेरणा उन्होंने देवीलाल से ली है. देवीलाल ने हरियाणा में किसानों के कर्जे माफ भी कर दिए हैं. कृषि पैदावार की कीमत को मूल्य सूचकांक से जोड़ने की बात उन्हें शेतकरी संघटना के शरद जोशी ने सिखाई है. वे खुद महाराष्ट्र में कपास की बेहतर कीमत के लिए जूझ रहे हैं.

किसान यूनियन ने रणनीति के तौर पर अपने आप को राजनैतिक दलों और दूसरे संगठनों से दूर ही रखा है. पहले भी देश के कुछ उन दूसरे इलाकों में भी ऐसा ही हुआ है जहां-जहां किसान एक बड़ी राजनैतिक ताकत बनते जा रहे हैं (देखिए इंडिया टुडे 30 नवंबर 1987). विश्वनाथ प्रताप सिंह (जनमोर्चा), हेमवती नंदन बहुगुणा (लोकदल-ब), मेनका गांधी (संजय मंच) और यहां तक कि चरण सिंह की विधवा गायत्री देवी समेत किसी को भी मंच पर टिकैत के पास जाने की इजाजत नहीं दी गई. वहां तक सिर्फ तांत्रिक चंद्रा स्वामी ही पहुंच सके क्योंकि वे किसी राजनैतिक दल के नहीं हैं. अगले चुनाव में किसान यूनियन की भूमिका की बात टिकैत बड़ी चालाकी से टाल जाते हैं. उनके समर्थक इस बात का खास तौर पर जिक्र करते हैं कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनसे टिकैत मंच से उतरकर मिलने आए.

टिकैत के इस करतब से दुविधा में फंसी उत्तर प्रदेश सरकार शायद अब देर-सबेर जाग गई है. आंदोलन ने बीर बहादुर को केंद्र से सलाह करने पर मजबूर कर दिया है. उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री बूटा सिंह, वित्तमंत्री नारायण दत्त तिवारी, शहरी विकासमंत्री मोहसिना किदवई और अखिल भारतीय इंका के महासचिव गुलाम नबी आजाद समेत कई नेताओं से बात की है. फिर भी वे पेशोपेश में पड़े लगते हैं.

बीर बहादुर की कार्रवाइयों से राज्य सरकार का दोगलापन जाहिर हो जाता है. एक तरफ वे टिकैत की खिंचाई करते हैं. "अगर हम बिजली के बिल माफ कर दें तो 900 करोड़ रुपए का खर्च आएगा. अगर गन्ने की कीमत बढ़ा दें तो 200 करोड़ रुपए और खर्च बैठेगा और चीनी मिलें भी बीमार हो जाएंगी. किसानों के लिए हम कई दूसरे राज्यों से ज्यादा बेहतर काम कर रहे हैं. टिकैत तो किसानों की आंखों में धूल झोंककर, उनसे नामुमकिन चीजों के वायदे करके नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं."

मुख्यमंत्री ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अपने दो मंत्रिमंडलीय सहयोगियों सईदुल हसन और हुकुम सिंह को किसानों से बातचीत के लिए कहा है. उन्होंने यह भी कहा है कि अगर किसान बातचीत चाहते हैं तो वे उनसे लखनऊ आकर बात कर सकते हैं. पर एक पूरे शहर पर कब्जा कर लेने के बाद किसान यूनियन के इरादे काफी ऊंचे हैं. यूनियन के महासचिव हरपाल सिंह मुस्कराते हुए कहते हैं, "हमारे लिए दिल्ली लखनऊ से ज्यादा नजदीक है."

—पंकज पचौरी, मेरठ में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

राजस्थान

दिग्गजों से मुंह मोड़ा

माथुर मंत्रिमंडल में संगठन के पदों पर बैठे लोगों का बोलबाला

पार्टी का हर पांचवां विधायक अब मंत्री हो गया है पर उनमें दिग्गज कोई नही है. इतना भारी-भरकम मंत्रिमंडल बनाकर और लगभग हर दिग्गज को उसकी औकात जताकर राजस्थान के नए मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर ने सत्ता की राजनीति पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने का जोरदार प्रयास किया है.

26 जनवरी को पहली खेप में सात और 6 फरवरी को दूसरी खेप में 13 विधायकों को मंत्री बनाकर माथुर ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं. (एक उपमंत्री भरत लाल मीणा इत्तला न मिल पाने की वजह से शपथ नहीं ले पाए हैं). इसके अलावा माथुर ने दो विधायकों को मुख्य सचेतक और उप सचेतक के पद दिए और तीन अन्य को संसदीय सचिव बनाया है. 21 मंत्रियों की फेहरिस्त में 13 पहली बार किसी मंत्रिपरिषद में आए हैं.

जिन दिग्गजों की ओर से माथुर ने आंखें फेर ली हैं उनमें हीरालाल देवपुरा, श्रीमती कमला बेनीवाल, नरेंद्र सिंह भाटी के अलावा जगन्नाथ पहाड़िया प्रमुख हैं. पहाड़िया को मंत्रिमंडल में आने का न्यौता जरूर मिला था लेकिन उन्हें ही यह रास नहीं आया. वे उपमुख्यमंत्री पद चाहते थे जिसके लिए माथुर राजी नहीं हुए. वे आएंगे, नहीं आएंगे, इस बारे में डेढ़ हफ्ते से चल रही अटकलें आखिर 5 फरवरी को इंका महासचिव गुलाम नबी आजाद के इस बयान से खत्म हो गईं कि पहाड़िया को केंद्र में कही खपाया जाएगा.

मनोज छाबड़ा

राज्यपाल जे.एस. वर्मा के साथ नया मंत्रिमंडल: नए-नए चेहरे

माथुर इसे इस तरह परिभाषित करते हैं, "आलाकमान पहाड़िया को पार्टी में ही कोई महत्वपूर्ण काम देना चाहता है." यह पूछे जाने पर कि फिर उन्होंने पहाड़िया से पूछे बिना ही मंत्री पद के लिए उनके नाम की घोषणा क्यों कर दी थी, माथुर ने कहा, "नहीं, बात तो मैंने की थी. बल्कि दोनों बार मंत्रिमंडल बनाने से पहले उनसे पूछा था."

पहाड़िया एक अन्य वजह से भी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए क्योंकि वे जानते थे कि मंत्री बनते ही भरतपुर आन्दोलन दबाने की जिम्मेदारी उनके माथे पर आन पड़ेगी, जिसे झुठला पाना उनके बस की बात नहीं होगी. पर सच पूछा जाए तो पहाड़िया के इस तरह राजस्थान से कट जाने से माथुर खेमा खुश ही है. यह बात दीगर है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी के खिलाफ लड़ाई में दोनों एक ही किश्ती पर सवार थे जिसमें पहाड़िया माथुर को अपना नेता मानने की घोषणा कर चुके थे. एक माथुर समर्थक की टिप्पणी थी, "पहाड़िया का नहीं शामिल होना ठीक ही रहा. उनके रहते मंत्रिमंडल में दूसरा शक्ति केंद्र उभरने की आशंका अब कुछ समय के लिए ही सही, टल गई है."

उधर देवपुरा को शायद मुख्यमंत्री पद का दावेदार होने की कीमत चुकानी पड़ी है. वर्ना 1967 के बाद से तो वे हर मंत्रिमंडल के आवश्यक अंग रहे हैं. राजनैतिक रूप से बेहद शक्तिशाली उदयपुर डिवीजन के दमदार प्रतिनिधि देवपुरा को किनारे करते समय माथुर ने यह ख्याल जरूर रखा कि इस काट-छांट से उदयपुर लॉबी नाराज न हो.

इस डिवीजन के इंका में सर्वाधिक 35 विधायक हैं. यही वजह है कि माथुर ने मंत्रिमंडल में देवपुरा के कट्टर विरोधी उदयपुर के हनुमान प्रसाद प्रभाकर को जगह दी. इसके अलावा उदयपुर शहर की विधायिका गिरिजा व्यास और सागवाडा-डूंगरपुर की कमला भील को राज्यमंत्री और उदयपुर के खेमराज कटारा को उपमंत्री बनाना इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है.

देवपुरा इससे खिन्न जरूर हैं पर फिलहाल

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं हैं. उनके एक खास सहयोगी ने कहा, "सारे नए लोगों को लेना पार्टी के लिए काफी नुकसानदेह हो सकता है, खासकर ऐसे वक्त में जब अगले चुनाव सिर पर हैं. देखते जाइए, यह सरकार कैसा कामकाज करके दिखाती है."

यही 'देखते रहने' की स्थिति कमला बेनीवाल की है. वे भी पिछले 15 साल से जाट नेता की हैसियत से हर मंत्रिमंडल में रही हैं. अब माथुर ने जाट नेता के रूप में शीशराम ओला को लिया है. जयपुर डिवीजन का प्रतिनिधित्व बेनीवाल से छीनकर 'पुराने कार्यकर्ता' भैरूंलाल भारद्वाज को दिया गया है.

मंत्रिमंडल में अब न ही कोई नरेंद्र सिंह भाटी का नामलेवा है. पहले चर्चा थी कि उनके 'जिगरी दोस्त' शिवराम शर्मा को जयपुर के प्रतिनिधि के हैसियत से मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी. पर माथुर ने जयपुर के प्रतिनिधित्व के लिए भारद्वाज के अलावा जयनारायण पैरवा (संसदीय सचिव) को चुनकर शर्मा को फिर अनदेखा कर दिया.

राजनैतिक विश्लेषण के हिसाब से जोशी समर्थकों का भी पूरी तरह सफाया हो गया है. वैसे वीना काक पदोन्नति पाकर राज्यमंत्री की हैसियत से मंत्रिमंडल में जरूर हैं लेकिन उन्हें अब जोशी समर्थक नहीं माना जाता. वक्त कुछ ऐसा बदला कि प्रधानमंत्री सचिवालय को माथुर का 'काला चिट्ठा' थमाने वाली काक अब उन्हीं के खेमे में पहुंच गई हैं. प्रेक्षक मानते हैं कि माथुर ने लगभग सभी 'दिग्गजों' का सफाया करके अपने रास्ते के कांटे हटाने का प्रयास किया है.

उधर राजस्थान के छह संभागों के आधार पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा सात मंत्री जोधपुर संभाग से हैं. यह अशोक गहलोत का अपना संभाग है. जिला स्तर पर जालौर जिले के तीनों इंका विधायकों को मंत्री पद सौंपा गया है. केंद्रीय गृहमंत्री बूटा सिंह के जालौर संसदीय क्षेत्र के अलावा कोई ऐसा जिला नहीं है जहां से सभी विधायकों को सरकार में शामिल किया गया हो. उदयपुर जिले से जहां इंका के सबसे ज्यादा 13 विधायक हैं, सिर्फ चार को मंत्री बनाया गया है. वहीं जोधपुर में पांच में से दो विधायक अब मंत्री हो गए हैं.

हालांकि शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए माथुर ने कहा था कि मंत्रिमंडल में सभी वर्गों, क्षेत्रों व जातियों का ध्यान रखा गया है लेकिन दस जिलों की पूरी तरह उपेक्षा की गई है जिनमें इंका के एक तिहाई से भी ज्यादा विधायक हैं. इन दस जिलों में जोशी का गृह जिला बांसवाड़ा और पहाड़िया का गृह जिला भरतपुर भी शामिल है. बांसवाड़ा से इंका के तीन और भरतपुर से पांच विधायक हैं. हर मंत्रिमंडल में जगह पाने वाला अलवर जिला भी इस बार उपेक्षित रहा है जहां से सात विधायकों के बावजूद एक को भी मंत्री नहीं बनाया गया.

राजनैतिक हलकों में जबरदस्त चर्चा का एक विषय माथुर की टीम में 'नए ही नए चेहरे' होना है. नौ कैबिनेट मंत्रियों में चार नए हैं और तीन राज्यमंत्री के ओहदे से पदोन्नत हुए हैं. दस राज्यमंत्रियों में से सात

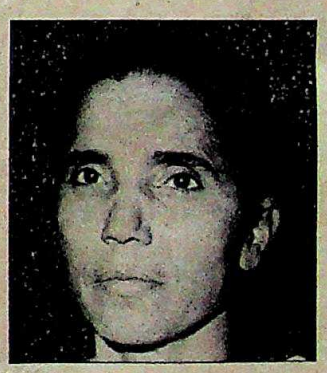

(ऊपर बाएं से) पहाड़िया, देवपुरा, बेनीवाल और भाटी: दिग्गजों की छुट्टी

नए हैं और दो उपमंत्री पद से पदोन्नत हुए हैं. दोनों उपमंत्री, सचेतक और तीनों संसदीय सचिव तो खैर नए हैं ही.

देवपुरा के साथी जहां इस टीम को 'अनुभवहीन' बता रहे हैं वहीं माथुर का कहना है कि 'टीम नई है पर कमजोर नहीं'. उनके दाहिने हाथ समझे जाने वाले कैबिनेट मंत्री बुलाकी दास कल्ला कहते हैं, "नए होने का मतलब अनुभवहीन होना नहीं है. कैबिनेट मंत्री माधो सिंह दीवान इंजीनियर हैं और जनलेखा समिति जैसी बॉडी के अध्यक्ष रह चुके हैं. दूसरे नए कैबिनेट मंत्री रघुनाथ विश्नोई इस समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं. इसी तरह राज्यमंत्रियों में लक्ष्मण सिंह वायुसेना के रिटायर्ड अफसर हैं और अंग्रेजी साहित्य के लेक्चरार भी रह चुके हैं. गिरिजा व्यास ढाई साल अमेरिका में लेक्चरार रहने के बाद चौदह साल से सुखाड़िया विश्वविद्यालय में लेक्चरार हैं."

नेतृत्व परिवर्तन में खास रोल अदा करने वाले प्रदेश इंका अध्यक्ष अशोक गहलोत ने भी 'खुशी' जाहिर की. पूछने पर उनका कहना था, "मैं तो पहली बार ही देख रहा हूं कि मंत्रिमंडल में संगठन के इतने सारे प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है. मंत्रियों में चार तो जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, एक सेवादल अध्यक्ष है. एक पार्टी उपाध्यक्ष भी है. मैं क्या, हमारी पार्टी के सारे कार्यकर्ता बेहद खुश हैं. उत्साह की जबरदस्त लहर आई है." उनकी टिप्पणी जाने-अनजाने इन चर्चाओं को भी बल देती है कि मंत्रिमंडल के गठन में उनकी 'इच्छा को खास महत्व दिया गया है.' राज्यपाल जे.एस. वर्मा द्वारा मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते समय एक इंका नेता ने टिप्पणी की भी, "अब अशोक जी की सरकार में शिवचरण माथुर मुख्यमंत्री बन गए हैं." अधिकांश विधायक इस बात से सहमत थे.

विडंबना ही है कि पिछले चुनावों से पहले माथुर को जोशी के पक्ष में मुख्यमंत्री की गद्दी खाली करनी पड़ी थी. तब यह माना जाने लगा था कि उनके बने रहने से इंका को हार का सामना करना पड़ेगा. पर अब राजनैतिक चक्र विपरीत दिशा में घूमा और जोशी को माथुर के लिए कुर्सी छोड़नी पड़ी.

जो भी हो, कई राजनैतिक प्रेक्षक अभी विधानसभा में 'माथुर सरकार का परफॉरमेंस देखना चाहते हैं.' नए लोगों पर भरोसा करने की माथुर की रणनीति कामयाब रही तो ठीक, वर्ना माथुर मंत्रिमंडल में कुछेक 'अनुभवी' लोगों को लेने की सोच सकते हैं. खुद उनके शब्दों में, "अगला विस्तार हुआ भी तो छोटा होगा और विधानसभा सत्र के बाद ही होगा."

बहरहाल जोशी मंत्रिमंडल के मुकाबले कैबिनेट का आकार बढ़ाकर और उसमें पार्टी के अनेक पदाधिकारियों को भर्ती करके माथुर ने सिद्ध कर दिया है कि विधायक का भी महत्व है.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पंजाब

मंदिर में मनमानी

आतंकवादियों की सक्रियता बढ़ी

गणतंत्र दिवस पर जब राज्य के सुरक्षा बलों के लोग आतंकवाद के खात्मे की कसमें खा रहे थे, कुछ सबसे खूंखार आतंकवादी जैसे पूरी राज्य व्यवस्था का खुल्लमखुल्ला मजाक उड़ा रहे थे. हरमंदिर साहिब के आसपास की सभी इमारतों के ऊपर उन्होंने केसरिया झंडे फहरा दिए जिन पर बड़े-बड़े काले अक्षरों में लिखा था— 'खालिस्तान.' उन्होंने गैस भरे गुब्बारे भी आसमान में छोड़े जिनसे लटके थे अलगाववादी पोस्टर. स्वर्णमंदिर के भीतर से आतंक, साजिश, यातना की खबरें फिर आने लगी हैं. ऐसे में कई पुलिस अधिकारी कहने लगे हैं कि एक बार फिर मंदिर में पुलिस का प्रवेश जरूरी है.

और कानून-व्यवस्था को जैसे ठेंगा दिखाते हुए पिछले महीने पंथिक कमेटी के एक सदस्य भाग सिंह ने मंदिर के अंदर मौजूद कुछ अरदासियों के बीच अलगाववादी पोस्टर बांटे. इन्हीं पोस्टरों में से एक में 'खालिस्तान' का नक्शा दिखाया गया है और भारत के नक्शे से जम्मू-कश्मीर और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कटा हुआ दिखाया गया है. नक्शे में कुछ महत्वपूर्ण शहरों के नाम भी बदल दिए गए हैं, जैसे दिल्ली का नाम 'दशमेश नगर' तो चंडीगढ़ का 'सतवंत नगर', हरिद्वार का 'भाई गुरदेव सिंह नगर' तो बंबई बंदरगाह का 'लिबरेशन पोर्ट' रखा गया है.

मगर स्वर्णमंदिर के भीतर जो कुछ हो रहा है वह इससे भी कहीं अधिक गंभीर मामला है. पुलिस सूत्रों का कहना है स्वर्णमंदिर के भीतर आतंकवादियों के 'पूछताछ सेल' में पिछले चार महीनों में करीब 10 लोगों को यातना देकर मार डाला गया. इनमें तीन औरतें भी थीं. जनवरी में ही ऐसी तीन वारदातें सामने आईं. डेरा बाबा नानक के हरजिंदर सिंह स्वर्णमंदिर में 2 जनवरी को अरदास करने गए थे और आतंकवादियों ने शुबहे के कारण उन्हें मार डाला. अमृतसर के चबाल की सुरिंदर कौर स्वर्णमंदिर में अपने कुछ परिचितों से मिलने गई थीं. 4 जनवरी को आतंकवादियों ने उनसे पूछताछ की. बताया जाता है कि दूसरे दिन उनकी हत्या कर दी गई. अमृतसर शहर की गुरवचन कौर 19 जनवरी की सुबह अरदास करने आईं तो फिर लौटी ही नहीं.

अधिकारियों को पूरा पता है कि स्वर्णमंदिर के भीतर कितने आतंकवादी हैं और उनकी गतिविधियां क्या रहती हैं. पंजाब के पुलिस महानिदेशक रिबेरो कहते हैं, "परिक्रमा वाले कमरों में करीब 60 आतंकवादी रह रहे हैं." खुफिया रिपोर्ट के अनुसार जनवरी के पहले हफ्ते में उनकी संख्या अचानक बढ़ गई.

और बावजूद इसके कि स्वर्णमंदिर के चारों ओर सुरक्षा सैनिक तैनात हैं, आतंकवादी अपनी गतिविधियां जारी रखे हुए हैं. उनकी प्रमुख गतिविधियां इस प्रकार हैं— हत्याओं की योजना बनाना, पैसे ऐंठने के लिए व्यापारियों व उद्योगपतियों को धमकी भरे पत्र लिखना, जिन पर पुलिस की मुखबिरी करने का शक हो उन्हें 'सजा' देना.

ऑल इंडिया सिख स्टुडेंट्स फेडरेशन के पैड पर भेजा गया धमकी भरा पत्र

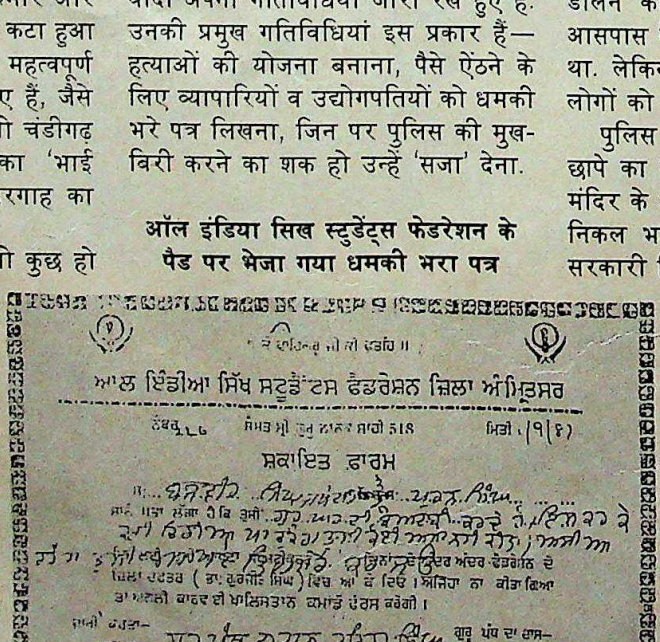

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਰਮ

ਸ੍ਰੀ ... ਸਪੁੱਤਰ ... ਨੂੰ ... ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ... ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ... ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ... ਦੇ ਖਿਲਾਫ ... ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ... ਤੁਹਾਨੂੰ ... ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ... ਜਿਸ ਦੱਤਰ (ਭਾ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ) ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਦਿਓ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ— ਗੁਰਪੰਥ ਦਾਸਨ ਦਾਸਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਦਾਸ—

ਜਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ

ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

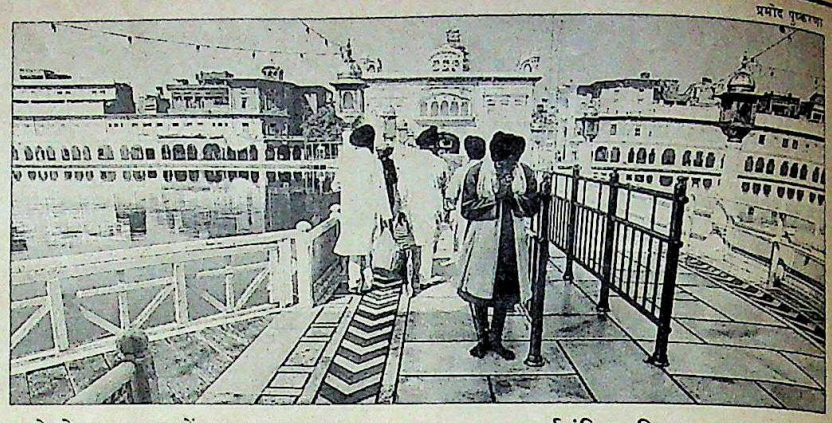

प्रभात गुप्तारा

स्वर्णमंदिरः फिर अड्डा बना

चंडीगढ़ के एक पुलिस अधिकारी के अनुसार आतंकवादी किसी-किसी दिन तो व्यापारियों, जमींदारों आदि से 10 लाख रुपए तक ऐंठ लेते हैं. उनके काम करने का ढंग सीधा और अचूक होता है. किसी आतंकवादी संगठन के पैड पर धमकी भरा पत्र लिखा जाता है कि अमुक तारीख तक इतने पैसे नहीं पहुंचाए गए तो पूरे परिवार का खात्मा कर दिया जाएगा. लगभग 95 फीसदी मामले में तो पैसा सीधे स्वर्णमंदिर में आतंकवादियों के हाथों में दिया जाता है. डर के कारण पुलिस को इस बारे में कुछ ही शिकायतें की जाती हैं. इजहार आलम कहते हैं, "हमें अंदर घुसने नहीं दिया जाता सो हम लाचार हैं." वास्तव में पुलिस ने 3 जनवरी की सुबह स्वर्णमंदिर पर छापा डालने की योजना बनाई थी. पुलिस ने आसपास के 60 लोगों को गिरफ्तार किया था. लेकिन कुछ घंटों बाद उनमें से आधे लोगों को छोड़ भी दिया.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि छापे का संदेह होते ही आतंकवादी स्वर्णमंदिर के आसपास घुमावदार गली-कूचों से निकल भागते हैं और वे अपने पास कई सरकारी विभागों के पहचान पत्र भी रखते हैं. कई आतंकवादियों ने अपने पास एसजीपीसी या अकाली दल के कार्यकर्ता होने का पहचान पत्र रखे हुए हैं.

और सबसे मुसीबत तो यह है कि पुलिस नागरिकों की परेशानी की वजह से हरेक पहचान पत्र की जांच नहीं कर सकती, और सुरक्षा सैनिकों को मंदिर में घुसने के अधिकार न होने के कारण आतंकवादी उनसे बेफिक्र अपनी मनमानी करते रहते हैं.

—**विपुल मुद्गल**, अमृतसर में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दिल्ली नगरपालिका

प्रशासक की पड़ताल

अधिकारियों के घरों, दफ्तरों पर सीबीआइ के छापे

हाल ही में जब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने नई दिल्ली नगरपालिका (एनडीएमसी) के अधिकारियों के घरों और कार्यालय पर छापे मारे तो लोगों को इस पर कोई खास हैरानी नहीं हुई. यह संस्था लंबे समय से भ्रष्टाचार के विवादों के घेरे में रही है. लेकिन इस बार चौंकाने वाली बात यह रही कि नगरपालिका के प्रशासक धर्मदत्त की भी छानबीन की गई है.

सीबीआइ ने उनके खिलाफ चार अन्य अधिकारियों से मिलकर एक गृहस्वामी पी.के. सोई को फायदा पहुंचाने के आरोप में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है. प्रथम दृष्टया सबूतों के अनुसार, स्थानीय नागरिक कानूनों का उल्लंघन कर सोई को 1,786 वर्ग फुट अतिरिक्त जमीन पर निर्माण की अनुमति दी गई. इससे सोई को 30 लाख से अधिक रुपए का फायदा हुआ.

प्रधानमंत्री के करीबी सतीश शर्मा से धर्मदत्त के करीबी संबंध हैं और इन दिनों वे इंजीनियरों के एक गुट से भिड़ गए हैं. इस गुट ने दो केंद्रीय मंत्रियों की सहायता से यह छापा डलवाया. वैसे धर्मदत्त घोषित कर चुके हैं कि छापे में उनके खिलाफ "कोई अनियमितता वाली चीज नहीं मिली."

हालांकि सतीश शर्मा प्रतिक्रिया के लिए उपलब्ध न हो सके, लेकिन उनके आलोचकों ने यह आरोप लगाकर बात को तूल दे दी है कि वे राजीव गांधी के चुनाव क्षेत्र अमेठी के लोगों को नौकरियों में खपाने के लिए धर्मदत्त के यहां भेजते रहे हैं. धर्मदत्त के समर्थक भी स्वीकार करते हैं कि नगरपालिका में भर्ती पर रोक के बावजूद 200 ऐसे व्यक्तियों को नौकरी दी गई. इसके अलावा कई लोगों को दुकानें और स्टॉल आवंटित किए गए.

नगरपालिका के सतर्कता विभाग ने इस नागरिक संस्था से संबंधित धोखाधड़ी के आरोपों की जांच करने पर पाया है कि विभाग के वरिष्ठ इंजीनियरों और ठेकेदारों के बीच मिलीभगत है. साथ ही बढ़ती हुई

सोई की विवादास्पद जमीन

: प्रशांत पंजियार

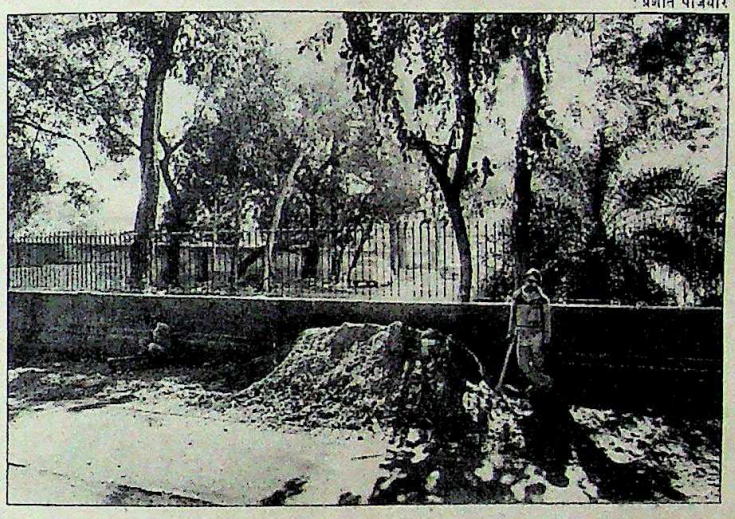

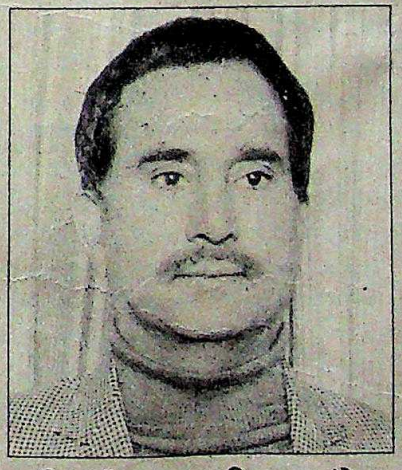

दिल्ली नगरपालिका लंबे समय से भ्रष्टाचार के विवादों में घिरी रही है लेकिन पहली बार सीबीआइ ने इसके प्रमुख धर्मदत्त के खिलाफ जांच शुरू की है

अंदरूनी लड़ाई में अपनी स्थिति को सुधारने के लिए प्रशासक धर्मदत्त ने समानांतर विभाग प्रमुख नियुक्त कर दिए हैं.

धर्मदत्त का कहना है कि अगस्त 1985 में अपनी नियुक्ति के बाद उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एक अभियान छेड़ा जिसकी वजह से ऐसे अधिकारी उन्हें निकलवाने के लिए लॉबीइंग कर रहे हैं. उनके द्वारा लिए गए कुछ फैसले भी आपत्ति के घेरे में हैं. इनमें दिल्ली के हृदय कहे जाने वाले कनाट प्लेस में मियानियों के अवैध निर्माण को नियमित करना शामिल है.

धर्मदत्त ने कहा, "मेरे कार्यभार ग्रहण करने से पहले 90 प्रतिशत मियानियों का अवैध निर्माण हो चुका था. और मैं इस घपले में अपने कर्मचारियों की मिलीभगत से भी इनकार नहीं करता. इन मामलों में कचहरी जाना व्यर्थ था, क्योंकि किसी मामले का फैसला होने में सालों लग जाते हैं. हमने मालिकों पर भारी जुर्माना लगाया और निर्माण को नियमित कर दिया."

1986 के मध्य से नगरपालिका ने 2 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि दंड के रूप में वसूली है. लेकिन असली फायदा तो व्यापारी वर्ग ने उठाया है. कुछ एनडीएमसी अधिकारियों के अनुसार उन्हें 20 करोड़ रुपए की कीमत की व्यापारिक महत्व वाली जमीन सस्ते में ही मिल गई.

धर्मदत्त की अध्यक्षता वाली समिति विशेष अनुरोध पर अनियमित निर्माण प्रारूपों को नियमित कर देती है. इस तरह के बहुत से मामले कनाट प्लेस स्थित रीगल बिल्डिंग में पाए गए थे और डी-74 तो बहुचर्चित हो ही गया है. इस इमारत का कोई रिकार्ड नगरपालिका के कार्यालय में उपलब्ध नहीं है और इसमें पांच स्थानों पर अवैध निर्माण हुआ है. धर्मदत्त ने सभी आपत्तियों को ठुकराते हुए पिछले साल इसके प्रारूप को अनुमति प्रदान कर दी.

दूसरा विवादास्पद फैसला अशोक शर्मा एसोसिएट्स को तीन साल के लिए बिजली के खंभों पर विज्ञापन लगाने की अनुमति दिए जाने का है. पिछले वर्ष बिना निविदाएं आमंत्रित किए और भारी राजस्व हानि के बावजूद मात्र 91,000 रुपए में लाइसेंस दे दिया गया. धर्मदत्त टालू अंदाज में कहते हैं, "यह कोई बहुत मुनाफे का धंधा नहीं है."

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

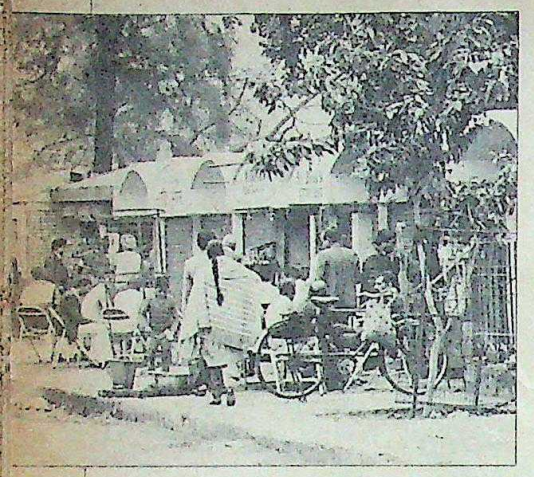

दुकानों के आबंटन में भी घपला

लेकिन 4,000 विज्ञापन बोर्डों पर लाइसेंस फीस 65 पैसे प्रतिमाह प्रति बोर्ड है जबकि फर्म द्वारा वसूल की जाने वाली कीमतों में यह फीस 300 से 500 रुपए प्रतिमाह है.

छोटी दुकानों और स्टालों का आबंटन भी फायदा पहुंचाने का अच्छा-खासा जरिया बन गया. फायदा पाने वाले मुख्य रूप से इंका और सेवादल के नेताओं के सगे-संबंधी हैं. अगर दुकान बेची जाए, तो उससे एक लाख रुपए और किराए पर देने पर 5,000 रुपए प्रति माह प्राप्त हो सकते हैं. एक वर्ष पूर्व 48 स्टाल विशिष्ट अतिथियों के रास्ते में आने के कारण तोड़ दिए गए थे. हटाए गए इन दुकानदारों को मुआवजे के रूप में दूसरे स्थानों पर स्टाल दिए गए. 200 स्टालों का निर्माण किया गया और फिर उन्हें बिना निविदाएं आमंत्रित किए आबंटित किया गया.

जवाबदेही का न होना एक ऐसा कारण है जिससे भ्रष्टाचार फैला है. विभागीय जांच और केंद्रीय गुप्तचर कमीशन की सिफारिशों की अधिकांशतः उपेक्षा ही की जाती रही है. धर्मदत्त स्वीकार करते हैं कि अनियमितताएं तो हैं लेकिन "कार्रवाई की जाती रही है." पिछले साल मुख्य रूप से 10 ग्रेड-ए अधिकारियों और 30 छोटे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई.

पर भीतरी सूत्रों का कहना है कि नगरपालिका में राजनैतिक दखलंदाजी के कारण दंडात्मक कार्रवाई में बाधा आती है. अब देखना है कि धर्मदत्त के खिलाफ मामले को जिस तरह से निबटाया जाएगा उससे क्या राजनीतिक अखाड़ेबाजी और भ्रष्टाचार दिल्ली के सत्ता दलालों की मदद से नई बुलंदियों पर पहुंचेंगे या नगरपालिका सही राह पर आ जाएगी. —पंकज पचौरी

बंबई

खेल का जुआ

वीडियो पार्लरों पर छापे

केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय भारत में जुआ-घर (कैसिनो) बनाने की योजना पर विचार कर ही रहा है कि बंबई में निजी 'वीडियो जुआघरों' की भरमार से अमेरिका के लास वेगास जैसी स्थिति बन गई है. लेकिन पिछले छह महीनों में यह धंधा जब सारी सीमाओं को तोड़ गया तो पुलिस को सक्रिय होना पड़ा. अभी तक 100 से अधिक वीडियो पार्लरों पर छापा मारकर चार करोड़ रुपए कीमत की करीब 1000 मशीनें जब्त की गई हैं.

इलेक्ट्रॉनिक मनोरंजन केंद्र चलाने का लाइसेंस सिर्फ 67 पार्लरों को मिला है पर किशोरवय लड़कों को आकर्षित करने वाले इस खेल के अड्डे हर गली-मुहल्ले में खुल गए हैं. चकाचौंध वाली ये मशीनें अब सिर्फ किशोरों की कुशाग्रता मापने की जगह उन्हें जुए की ओर प्रेरित करने लगी हैं. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) अरविंद इनामदार बताते हैं, "इसी बात से हमने यह सारा धंधा बंद करने की कोशिश शुरू की. हमें कई अभिभावकों और अध्यापकों से इस बारे में शिकायत मिली है."

बंबई पुलिस को जो शिकायतें मिलीं उनमें, अपने 19 वर्षीय बेटे के साथ बंबई आई दिल्ली विश्वविद्यालय की एक प्रोफेसर की शिकायत सबसे जोरदार थी. वे अपनी बीमार मां की देखरेख के लिए यहां आई और उन्होंने बेटे को 8000 रुपए रखने के लिए दिए थे. पर लड़के ने इलेक्ट्रॉनिक जुए के चक्कर में यह सारी रकम गंवा दी. अपनी शिकायती चिट्ठी के अंत में इस प्रोफेसर ने लिखा, "बेटे को नियंत्रित न रख पाने के लिए मैं खुद को भी दोषी मानती हूं." पुलिस ने शिकायत मिलते ही छापा मारा और सभी मशीनों को जब्त कर लिया.

मुख्य रूप से चार तरह की मशीनें नौजवानों को जुआ खेलने के लिए उकसाती हैं. 'गोल्डेन डर्बी' अपने दांतदार चक्र से तुरत फैसला देती है, 'स्काइबाल' खेलने वाले के भाग्य की परीक्षा गुल्लक में गेंद डालकर करती है और 'बाली लकी बार' जिसे 'एक बांह वाला लुटेरा' कहा जाता है, आम जुआघरों में संख्या के आधार पर जुआ खेलने जैसी मशीन है. पर किशोरों को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है कलर स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉनिक ताश की तरह का खेल दिखाने वाली 'गुडलक' मशीन.

पिछले महीने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के एक कंप्यूटर वैज्ञानिक ने दो दिनों तक 'गुडलक' गेम का टेस्ट किया. चार अलग-अलग मशीनों पर 1101 बार दांव लगाने के बाद उनका निष्कर्ष था कि घंटों खेलने के बाद भी जीतने की संभावना शून्य ही रहती है. पुलिस कार्रवाई के खिलाफ वीडियो पार्लर मालिकों ने बंबई हाईकोर्ट में जो मुकदमा दायर किया था उसके खिलाफ इस वैज्ञानिक के निष्कर्षों का भी इस्तेमाल किया गया.

ताइवान से थोड़े से पुर्जे मंगाकर अब ये तमाम मशीनें भारत में ही बनाई जा रही

मनदीप पारीक

स्कूल के बजाय वीडियो पार्लर में

हैं. हर मशीन की कीमत 50,000 रुपए है.

इस धंधे में मांग व मुनाफे की संभावनाएं इतनी ज्यादा हैं कि हाल में एक प्रमुख टीवी कंपनी ने भी इस क्षेत्र में उतरने का फैसला किया. पुलिस के अनुसार मौके की जगहों पर लगे पार्लर रोजाना करीब 50,000 रुपए कमा लेते हैं जबकि जुए के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनें महीने में 10,000 रुपए का मुनाफा देती हैं. सहायक पुलिस आयुक्त मीनू ईरानी ने कहा, "यह फैशन अब दूसरे शहरों और छोटे हिल-स्टेशनों पर भी फैल रहा है."

पर जिस तरह से पुलिस ने 'वीडियो जुआ' पार्लरों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है उससे पार्लर मालिकों को लग गया होगा कि यह खेल अब उन्हें महंगा पड़ने जा रहा है. —एम. रहमान

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तमिलनाडु

बढ़ती उलझन

आरोपों की नई बरसात

फरवरी माह शुरू होते ही तमिलनाडु की फिजा और गर्म हो उठी. पिछले कुछ हफ्तों से वहां राजनैतिक उलट-फेर का सिलसिला अंतहीन बना हुआ है. पी.सी. अलेक्जेंडर नए राज्यपाल बनाए गए. उनके साथ ही उनके दो सलाहकार—पूर्व केंद्रीय नागरिक उड्डयन सचिव एस.एस. सिद्धू और राज्य के पूर्व मुख्य सचिव ए. पद्मनाभन नियुक्त हुए. इन लोगों के लाए जाने से यह उम्मीद की जाने लगी है कि इंका समय से पहले ही राज्य विधानसभा का चुनाव कराने की इच्छुक है. और अभी से राजनैतिक दलों में तालमेल की बातचीत शुरू हो गई है.

इस दौरान जानकी गुट को बदनाम करने की मुहिम भी पूरे जोर-शोर से चल पड़ी है. इंका के सात सांसदों ने अलेक्जेंडर के पूर्ववर्ती सुंदरलाल खुराना को एक ज्ञापन दिया कि 24 दिन के शासन में जानकी सरकार के मंत्रियों ने खूब चांदी काटी है.

आरोप था कि जानकी सरकार के आठ मंत्रियों ने लंबे समय से लटकी पड़ी फाइलों को निबटाने में जरूरत से ज्यादा रुचि ली. उन्होंने चंदा लेने वाले और स्वाश्रयी पांच नए इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की मंजूरी दी, नए बस रूट चलाने और भारत निर्मित विदेशी शराब की दुकानें खोलने के लाइसेंस दिए. और यह सब कुछ चुनींदा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया. राजभवन के एक सूत्र के मुताबिक, "राष्ट्रपति शासन लगने के बाद जब राज्यपाल ने शासन का कार्यभार संभाला तो उन्होंने अल्पकालीन जानकी सरकार के दौरान निबटाई गई सभी फाइलों पर पुनर्विचार के आदेश दिए."

करीब दो साल से इंजीनियरिंग कॉलेजों की मंजूरी के लिए लटके पड़े आवेदनों को कलम की एक ही जुंबिश में मंजूरी दे दी गई. प्रस्तावित कॉलेजों में रुचि लेने वालों में अमेरिका स्थित एक प्रमुख आप्रवासी भारतीय हैं (वे दिवंगत मुख्यमंत्री रामचंद्रन और उनकी पत्नी जानकी के करीबी माने जाते हैं).

और फिर जानकी सरकार के आबकारी मंत्री वी.वी. स्वामीनाथन ने राज्य भर में 23 नई दुकानों को भारत निर्मित विदेशी शराबों के लाइसेंस दिए थे. पिछले साल जब 1,700 ऐसे आवेदन मंजूर किए गए थे तो इन 23 दुकानों को विभिन्न कारणों से लाइसेंस नहीं दिया गया था. इनमें एक कारण तो यही था कि ये प्रस्तावित दुकानें शैक्षिक संस्थानों या पूजास्थलों के बहुत ही नजदीक पड़ती थीं.

हालांकि एक या दूसरे नेता की सिफारिश से आए इन सभी आवेदकों ने अपनी पुरानी योजना बदलकर नई जगहों का चुनाव कर लिया था, फिर भी कुछ बातें काफी हैरतअंगेज हैं. असंख्य फाइलों और पुनर्विचार के मामलों को छोड़कर इन्हें ही कृपा का पात्र क्यों समझा गया, यह एक रहस्य है. मजेदार बात यह है कि नए लाइसेंस प्राप्त करने वालों में कुछ तो तिरुरनेलवेली जिले के हैं. इसी जिले के चेरनमहादेवी क्षेत्र से पांडियन विधायक हैं.

स्वामीनाथन ने इन आरोपों का पुरजोर खंडन किया. उन्होंने कहा, "मैंने फाइलों पर हस्ताक्षर संबंधित विभागों से विस्तृत ब्यौरा और सुझाव प्राप्त करने के बाद ही किए. इसलिए इस गड़बड़झाले के लिए मुझ पर आरोप मढ़ना हास्यास्पद है. और फिर अगर सही मामलों में भी हम मंजूरी नहीं देते तो लोग अदालतों का दरवाजा खटखटाकर मंजूरी हासिल कर लेंगे."

मद्रास में अन्नाद्रमुक के जानकी और जयललिता गुटों ने एक-दूसरे पर सिर्फ ये आरोप ही नहीं उछाले. जयललिता ने पूर्व परिवहनमंत्री एस. मुथुस्वामी पर रामचंद्रन के इलाज के लिए अमेरिका यात्रा के खर्च का भुगतान करने के लिए 1987 में बस मालिकों से पांच करोड़ रुपए इकट्ठा करने का आरोप लगाकर इस तमाशे की शुरुआत की. आरोप था, "यह रकम सरकार को सुपुर्द नहीं की गई. पार्टी के खजांची एस. माधवन के पास अभी एक करोड़ और मुथुस्वामी के पास दो करोड़ रुपए हैं."

पूर्व मंत्री ने अपने को आरोप से बरी करने के लिए जांच बैठाने की मांग की है. माधवन का कहना है कि अन्नाद्रमुक ने 1984 में रामचंद्रन की अमेरिका यात्रा और फिर 1985 में उनके गुर्दे के प्रत्यारोपण के लिए चंदा इकट्ठा किया था. मुथुस्वामी कहते हैं, "करीब 1.5 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए थे जिसमें से एक करोड़ सरकार को ऋण भुगतान के एवज दिए गए. बाकी रकम सावधि जमा के रूप में बैंक में पड़ी है." लेकिन अपने आरोप पर कायम जयललिता ने केंद्र सरकार से कई पूर्व मंत्रियों की चल संपत्ति की भी जांच कराने की मांग कर डाली है.

श्याम टेकवानी

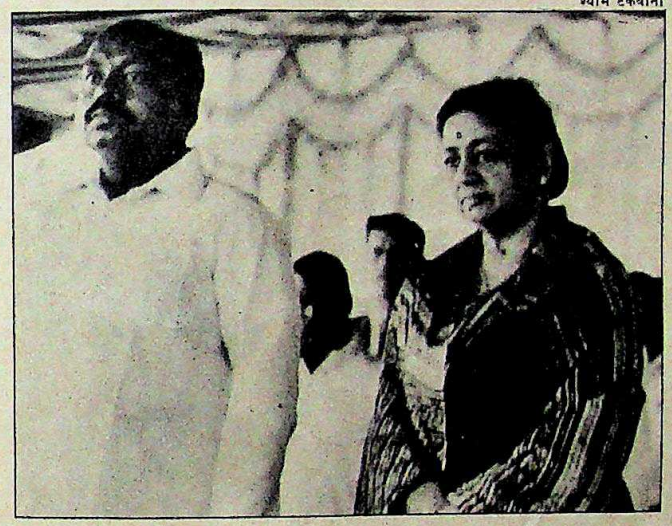

जानकी और पांडियनः गंभीर आरोप

समय से पहले विधानसभा चुनाव होने की संभावनाओं के साथ ही अन्नाद्रमुक के जानकी गुट को बदनाम करने की मुहिम भी जोर-शोर से चल पड़ी है

अन्नाद्रमुक गुटों के इस आपसी झगड़े से सबसे खुश द्रमुक के अध्यक्ष एम.करुणानिधि हैं. वे कहते हैं, "रामचंद्रन और उनके मंत्रियों पर मैंने भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए थे, अब उन्हें खुलेआम कबूल किया जा रहा है. अब मुझे तो वे आरोप दुहराने की जरूरत ही नहीं रह गई."

पिछले महीने विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के वक्त इंका की दगाबाजी के बाद जानकी गुट को अब द्रमुक में कई समानताएं दिख रही हैं. करुणानिधि की पार्टी की तरह वह भी अब क्षेत्रीय भावनाओं को उभारना चाहती है. अब

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

एकाएक उसे भारत-श्रीलंका समझौता भी असहज मालूम पड़ने लगा है.

पर करुणानिधि का कहना है कि उनका दल अन्नाद्रमुक के दोनों गुटों में से किसी के साथ संबंध नहीं रखना चाहता. वे कहते हैं, "हम अकेले ही अपनी गाड़ी चलाए रखने की तैयारी कर रहे हैं." लेकिन जानकार लोग जानकी गुट और द्रमुक के बीच एक तरह के चुनावी तालमेल की संभावना से इनकार नहीं करते.

दूसरी तरफ जयललिता गुट और इंका के बीच का मामला भी अभी पूरी तरह साफ नहीं हो पाया है. हालांकि उनके बीच मैत्री स्वाभाविक है फिर भी मामला वहां अटक रहा है जहां अन्नाद्रमुक का यह गुट इंका पर हावी होना चाहता है क्योंकि फिलहाल तमिलनाडु में जयललिता ही भीड़ जुटाने में सबसे अधिक कारगर हैं. उनके गुट के पूर्व मंत्री वी.आर. नेदुनचेडियन कहते हैं, "इंका को चाहिए कि अगले चुनाव में सीटों के बंटवारे में हमारे साथ पहले-सा ही तालमेल बनाए रखे."

लेकिन इंका पर इसका रत्ती भर प्रभाव नहीं पड़ा है. पार्टी के एक दिग्गज कहते हैं, "जयललिता की व्यक्तिगत लोकप्रियता अभी साबित होनी बाकी है."

इंका में असंतोष उभर आने से भी हालात अधिक पेचीदा हो गए हैं. पिछले पखवाड़े राज्य युवा इंका के पूर्व अध्यक्ष जगवीर पांडियन ने विश्वनाथ प्रताप सिंह के समर्थन में पूर्व राज्यमंत्री जी. बुवाराघवन के साथ मिलकर कई वकीलों और पार्टी कार्यकर्ताओं सहित पार्टी छोड़ दी.

यह भी कहा जा रहा है कि इंका के राष्ट्रीय महासचिव जी.के. मूपनार को राज्य में पार्टी अध्यक्ष बनाकर भेजा जा रहा है. इससे इंका नेता मिलजुलकर काम करने की जरूरत महसूस करने लगे हैं. उन्हें यह भी तय करना होगा कि द्रमुक और जानकी गुट द्वारा भड़काई जाने वाली क्षेत्रीय भावनाओं को वे कैसे काबू कर पाएंगे. इसके साथ ही उनके सामने जयललिता का सवाल भी है. इस पखवाड़े के बीतते-न-बीतते जितने सवाल हल हुए हैं, उससे कहीं अधिक उठ खड़े हुए हैं.

—एस.एच. वेंकटरमनी

तमिल चीते

पनाहगाह की खोज

तमिलनाडु अब तमिल मुक्ति चीतो की सुरक्षित मांद नहीं रह गई है. उनको शरण देने और पालने-पोसने वाले पूर्व मुख्यमंत्री एम.जी. रामचंद्रन के निधन से वे अनाथ हो गए हैं. पिछले पखवाड़े राज्य में लगे राष्ट्रपति शासन ने तो उन्हें पनाहगाहें तलाशने पर मजबूर कर दिया है. अब सेना और केंद्रीय खुफिया एजेंसियां तमिलनाडु सरकार को वहां श्रीलंकाई तमिल गुरिल्ला संगठनों के बचे-खुचे तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए जोर दे रही हैं.

पिछले पखवाड़े दक्षिणी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल देपिंद्र सिंह जब राज्य के मुख्य सचिव (अब राज्यपाल के सलाहकार) ए. पद्मनाभन से मिले तो माहौल में काफी गरमी पैदा हो गई. उन्होंने शिकायत की कि 25 जनवरी को तंजावुर जिले में वेदारन्यम शहर के पास गिरफ्तार संदिग्ध मुक्ति चीतों के प्रति राज्य पुलिस नरमी से पेश आ रही है. इन लोगों को चुंगी अधिकारियों द्वारा काली-मीर समुद्रतट के नजदीक एक खाली खड़ी स्टैंडर्ड-20 वैन को कब्जे में लेने के बाद हिरासत में लिया गया था. वैन से उन्होंने 20 आरपीजी-7 रॉकेट लांचर, एक वाकी-टाकी सेट और फौजी वर्दी के लिए हरा 200 मीटर कपड़ा बरामद किया था.

जनरल ने राज्य में मुक्ति चीतों और दूसरे उग्रवादी संगठनों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने में पुलिस की अक्षमता की भी शिकायत की. इस बैठक में जाफना में मुक्ति चीतों के पूर्व क्षेत्रीय कमांडर किट्टू को मद्रास में नजरबंदी के दौरान चोरी-छिपे एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर इस्तेमाल करने की इजाजत देने का सवाल भी उठाया गया.

पर पुलिस ने आरोप का खंडन किया है. उसका दावा है कि उग्रवादियों को पकड़ने के एक अभियान में उन्होंने बट्टीकलोआ के 24 वर्षीय अरविंदन के

श्याम टेकवानी

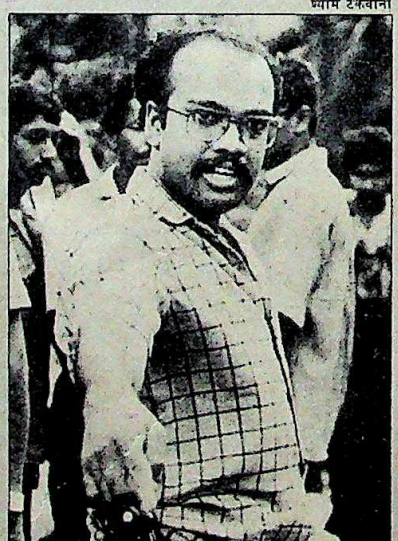

मुक्ति चीतों के नेता किट्टू

अलावा जाफना के 22 वर्षीय शांताकुमार और 28 वर्षीय जीवाज्योति को गिरफ्तार किया था. उनके पास से शांति सेना विरोधी साहित्य और वैध दस्तावेजों के बिना कर योग्य विदेशी सामान बरामद किया गया था. पुलिस के महानिदेशक के. रवींद्रन कहते हैं, "हम कह नहीं सकते कि ये संदिग्ध व्यक्ति मुक्ति चीतों के ही सदस्य हैं." इस बीच जांच से पता चला कि इन तीनों में से अरविंदन सचमुच मुक्ति चीतों का सदस्य था.

रामचंद्रन होते तो ऐसी घटना रफा-दफा कर दी जाती. लेकिन स्थिति अब पूरी तरह बदल गई है. अक्तूबर में भारतीय शांति सेना और तमिल मुक्ति चीतों के बीच जाफना में लड़ाई छिड़ने के बाद तो स्थिति और बिगड़ गई. तब से तमिलनाडु में रहने वाले करीब 5,000 उग्रवादियों में से ज्यादातर श्रीलंका लौट चुके हैं. पिछले पखवाड़े राज्य में रह रहे उग्रवादियों की संख्या मात्र 400 रह गई. इनमें 120 मुक्ति चीतों के और 80-80 'पीपुल्स लिबरेशन आर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल ईलम' और 'तमिल ईलम लिबरेशन आर्गेनाइजेशन' के सदस्य हैं. इसलिए आशंका है कि समझौते के बाद मुक्ति चीते अपने सभी हथियार धीरे-धीरे श्रीलंका ले जाने लगे. मुक्ति चीतों के प्रमुख सूत्र मानते हैं कि वैन में पकड़ा गया सामान श्रीलंका ले जाई जाने वाली अंतिम खेप थी.

इसके पीछे नई दिल्ली के नीति निर्माताओं का तर्क शायद यह है कि भारत-श्रीलंका समझौते के अलोकप्रिय पहलुओं को अमल में लाने का यही वक्त है, खासकर जब राष्ट्रपति शासन के कारण यह सब करने का अधिकार उन्हें मिल गया है. लेकिन वक्त उनका साथ नहीं देगा क्योंकि चुनाव की घोषणा होते ही इंका को लोकप्रिय मुद्रा अपनानी पड़ेगी. और तमिल चीतों की धर-पकड़ इस मंशा को पूरा नहीं कर पाएगी.

—एस.एच. वेंकटरमनी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गोरखा आंदोलन

समझौते का संकट

सभी पक्ष मामला सुलझाने के बजाय राजनैतिक लाभ की ताक में

दार्जिलिंग पहाड़ियों के माहौल को शांत करने का एक और मौका हाथ से निकल गया. समाधान की जो उम्मीदें बन रही थीं वह पिछले महीने अचानक ही चरमरा गईं. और जैसे ही पहाड़ियों पर 40 दिन का बंद शुरू होगा हालात फिर से तेजी से बिगड़ने लगेंगे.

केंद्रीय गृहमंत्री बूटा सिंह, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु और गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष सुभाष घीसिंग 25 जनवरी को नई दिल्ली में पहली बार मिले. वे मुस्कराते हुए, फिर मिलेंगे के वायदे के साथ बैठक से निकले.

पर यह मुस्कान उनके मतभेदों को छुपा न सकी. वे इतना भी नहीं तय कर सके कि फिर कहां मिलेंगे. घीसिंग ने 'मार्क्सवादी राजधानी' कलकत्ता जाने की बात नहीं मानी, वे दिल्ली आना चाहते थे 'जहां मध्यस्थ रहते हैं'. चिढ़े हुए बसु का आरोप था कि घीसिंग लगातार अपना रवैया बदल रहे हैं. पर बंगाल सरकार यह मानती है कि घीसिंग दिल्ली पहुंचकर उदारवादी हो जाते हैं और घर लौटते ही लड़ाकू.

दार्जिलिंग के जलपहाड़ स्थित अपने मुख्यालय में बैठे आंदोलनकारी घीसिंग को नई दिल्ली और कलकत्ता में ही सारी बुराई नजर आती है, "एक बार तो हम समझौते पर दस्तखत करने के लिए तैयार हो गए थे. लेकिन केंद्र और राज्य सरकार तो बस राजनीति ही खेलना चाहती हैं." वे चेतावनी देते हैं कि, "अगर बसु हमारी कम कर दी गई मांगों को भी नहीं मानते तो नतीजों की जिम्मेदारी उन पर ही होगी."

राज्य की राजधानी में लौटकर बसु ने कहा कि वे दूसरे राजनैतिक दलों से मिलकर पर्वतीय विकास परिषद बनाएंगे, गोरखा मुक्ति मोर्चा चाहे कुछ भी कहता रहे. दिल्ली में बातचीत का मकसद था एक ऐसा समाधान तैयार करना जिसमें गोरखा बहुल पहाड़ी इलाकों को थोड़ी-बहुत स्वायत्तता मिलने का इंतजाम हो. समाधान के तौर पर पश्चिम बंगाल सरकार ने पर्वतीय विकास परिषद का प्रस्ताव रखा था. पर कुछ छोटे-छोटे मुद्दों पर सहमति नहीं बन सकी. बातचीत नाकाम हो गई.

दार्जिलिंग में घीसिंग का दबदबा कम होता देखकर ही शायद बसु ने यह घोषणा कर दी. वहां पर राज्य सरकार की नीतियां बनाने वाले जिलाधीश देवी प्रसाद पात्रा (33) एक तीसरी ताकत— गोरखा संग्राम परिषद— खड़ी करने में करीब-करीब कामयाब हो गए हैं. घीसिंग को दूसरी जगहों में भी विरोध झेलना पड़ रहा है. कुर्सियांग में तो उनके विरोधियों ने उनके खिलाफ एक प्रदर्शन तक कर डाला. प्रांत परिषद के पूर्व नेता मदन तमांग घीसिंग के नेतृत्व को चुनौती दे रहे हैं. वे पूछते हैं कि घीसिंग को पर्वतीय परिषद के लिए बातचीत का क्या अधिकार है, जबकि वे पहले ही गोरखालैंड का वायदा कर चुके हैं.

पर मोर्चे के अध्यक्ष अपने दबदबे को लेकर आश्वस्त हैं. घीसिंग कहते हैं, "ये गुस्से से भरे हुए लोग हैं. इनमें पुलिस वालों के खिलाफ नफरत है, जिन्होंने इनके घर जला दिए और इन्हें भूमिगत होने पर मजबूर कर दिया. मैं निश्चित हूं कि मैं उन्हें पर्वतीय परिषद स्वीकार करने के लिए मना लूंगा." उन्होंने मोर्चा और इसके संगठनों के कई पदाधिकारियों को हटाने का आदेश दिया है. दूसरी तरफ मोर्चे को पुलिस की मार झेलनी पड़ रही है. मोर्चे के 300 समर्थकों को उनके ठिकानों से गिरफ्तार किया गया है और ज्यादातर के खिलाफ आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. इतने ज्यादा लोग भूमिगत हो गए हैं कि औरतों को उनकी जगह लेनी पड़ रही है. मोर्चे के प्रधान घीसिंग का कहना है, "अगर पुलिस ने औरतों को भी गिरफ्तार करना शुरू कर दिया तो मुझे वार्ता के लिए फ्राक और निक्कर पहनने वाले बच्चों को लेकर ही दिल्ली जाना पड़ेगा."

पर पुलिस कुछ और ही बात कहती है. कुर्सियांग के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आर. के. पचनंदा बताते हैं कि उन्हें मिली खबरों के मुताबिक मोर्चा के आत्मघाती दस्ते शिविरों में प्रशिक्षण पा रहे हैं. वे बताते हैं, "हमने इन शिविरों में कई खाइयों को भरा

घीसिंग का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकारें निहित स्वार्थों के कारण राजनैतिक चाल चल रही हैं

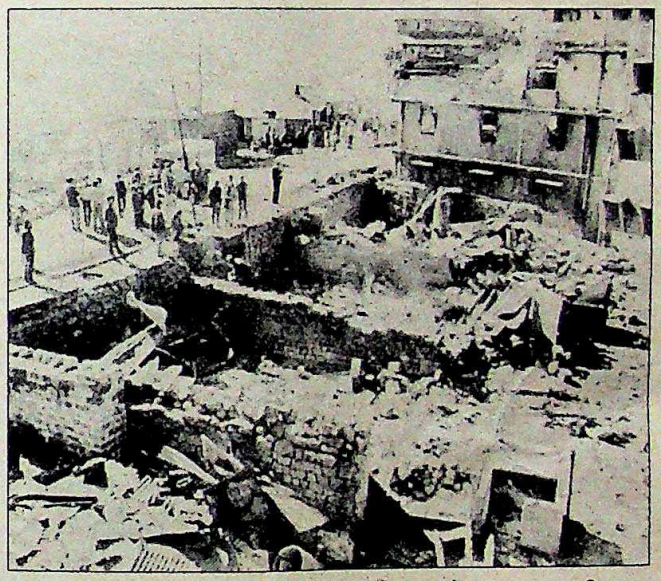

कुर्सियांग जिले में जलाए गए घर

और राज्य सरकार के जिलाधीश पात्रा एक तीसरी ताकत खड़ी कर रहे हैं

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

और ढेर सारे हथियार बरामद किए. इनमें भारी विस्फोटक, स्टेनगन, सेल्फ लोडिंग रायफलें, जिलेटिन स्टिक व देसी बम भी हैं.

घीसिंग ने यह भी कहा कि अगर मोर्चे की मांगें फिर भी नहीं मानी गईं तो मोर्चा पर्वतीय विकास परिषद का प्रस्ताव भी ठुकरा देगा और फिर से अलग राज्य की लड़ाई छेड़ने पर मजबूर होगा.

मोर्चे की मांग है कि प्रस्तावित पर्वतीय विकास परिषद में ज्यादा इलाका शामिल किया जाए, परिषद के नाम में गोरखा शब्द शामिल किया जाए और इसकी संवैधानिक गारंटी दी जाए कि परिषद को कलकत्ता की दया पर नहीं जीना पड़ेगा. इन्हीं मांगों की वजह से समाधान खटाई में पड़ गया था.

सरकार के रवैये को दोहराते हुए पात्रा कहते हैं कि परिषद में किसी मैदानी इलाके को शामिल करने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि यह तो खास तौर पर पहाड़ी लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए बनाई जाएगी. 'भाषाई आधार पर नहीं.'

'गोरखा' शब्द शामिल करने का मामला भी गंभीर है. कलिम्पोंग आदिवासी संगठन, दार्जिलिंग का लेपचा संगठन और पर्वतीय अल्पसंख्यक संघ इसका विरोध कर रहे हैं. डर है कि इससे गोरखों का नेपालियों, भूटानियों, तिब्बतियों, लेपचाओं और दूसरे समुदायों से तनाव बढ़ सकता है.

ये मुद्दे हल भी हो गए तो समस्या खत्म नहीं होगी. घीसिंग इस सिलसिले में स्पष्ट हैं कि वे अपनी बाकी मांगें नहीं छोड़ेंगे. हालांकि भारत-नेपाल संधि अभी रद्दी की टोकरी के हवाले नहीं की गई पर घीसिंग का दावा है कि केंद्र ने एक गजट अधिसूचना जारी करने का वायदा किया है. यह अधिसूचना भारतीय गोरखों को नेपाली गोरखों से अलग रखने के लिए जारी की जाएगी. घीसिंग बताते हैं, "नेपाली को संवैधानिक भाषा का दर्जा देने की मांग को भाषा समिति देखेगी. और अलग राज्य की मांग तो तब तक जारी रहेगी जब तक संविधान इसकी इजाजत नहीं देता."

इस बीच वाम मोर्चा और केंद्र सरकार एक दूसरे को गरियाने में जुट गए हैं. वाम मोर्चा के अध्यक्ष सरोज मुखर्जी ने राजीव गांधी पर गोरखा मुक्ति मोर्चे को भड़काने का आरोप लगाया है जबकि राजीव का कहना है कि बंगाल सरकार समस्या से गलत ढंग से निपट रही है. दोनों पक्षों की दिलचस्पी मामला सुलझाने से ज्यादा राजनैतिक फायदे उठाने में है और पहाड़ियों में शांति की बात अब दूर होती जा रही है.

—कमलजीत रतन, दार्जिलिंग में

कर्नाटक

हरिजन होना गुनाह

जनता सरकार में जुल्म बढ़ा

कर्नाटक के शिमोगा जिले के टत्तूर गांव का हरिजन कुली चंद्रप्पा (35) 29 जनवरी को कभी नहीं भूल सकेगा. उस दिन ऊंची जाति के हिंदुओं ने उसे पीटा और अपमानित किया. उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि वह हरिजन है. उसे खंभे से बांधकर लगातार पीटा गया, मैले में लिपटी हुई एक बेकार चप्पल उससे जबरन चबवाई गई.

श्रीनिवास कुमार

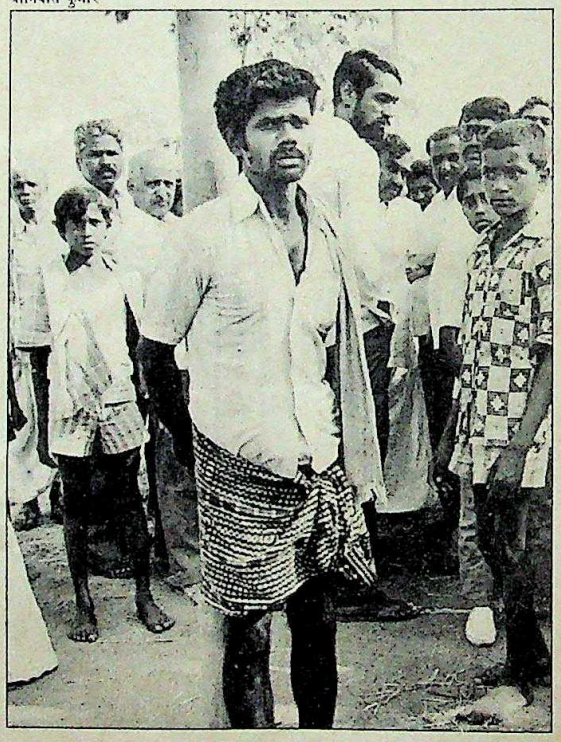

यह जघन्य घटना कर्नाटक के दलितों के लिए मरने-जीने का सवाल बन गई. लगभग सभी पार्टियों के नेता भी सदमा और पछतावा जताते हुए टत्तूर (आबादी: 1,000) पहुंचने लगे. मैसूर में एक स्कूल के दलित छात्रों ने विधानसभा अध्यक्ष बी.जी. बानाकर को जा घेरा, उनकी खिड़कियां तोड़ीं और खून की नदियां बहा देने की धमकी दी.

अभी तक तो टत्तूर के सवर्ण हिंदू ही स्पष्ट रूप से इसके गुनहगार दिख रहे हैं. अंदर तक हिल गए चंद्रप्पा ने बताया कि यह सब तब शुरू हुआ जब गांव के पुजारी ने उसकी बीवी गुथिअम्मा को पूजा की इजाजत नहीं दी और कह दिया कि तुम्हारे लिए मेरे पास समय नहीं है. नाराज चंद्रप्पा कारण जानने के लिए मंदिर जा धमका. बस यही वजह बन गई. और तुरंत ही तमाशाइयों की भीड़ जुट गई. इनमें टत्तूर जनता पार्टी मंडल पंचायत के सदस्य रविशंकर गोवदा (32) भी थे. गोवदा के कहने पर उस पर तमाम अत्याचार किए गए.

चंद्रप्पा बताता है कि "हर कोई चुपचाप देख रहा था." बाद में दो हरिजनों ने उसे खोला. अपमानित और गुस्से से भन्नाए हुए चंद्रप्पा ने अगले ही दिन शिकायत दर्ज कराने का फैसला कर लिया.

30 जनवरी को जब मंडल पंचायत की बैठक हो रही थी तो चंद्रप्पा वहां जा पहुंचा. उसके हाथ में एक तख्ती थी जिस पर

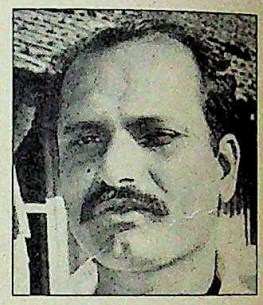

(बाएं) घटना का बयान करते चंद्रप्पा; और (ऊपर) रविशंकर गोवदा

गोवदा की निंदा की गई थी. गोवदा के लोगों ने तख्ती जला दी. चंद्रप्पा ने तब अनावत्ती थाने में रपट दर्ज कराई और एक फरवरी को पुलिस ने गोवदा समेत 11 लोगों को नागरिक अधिकार रक्षा अधिनियम की धारा 7 (छुआछूत पर रोक) के तहत गिरफ्तार कर लिया. बाद में उसी दिन सभी छोड़ दिए गए.

टत्तूर में वही हुआ जो पिछले साल अगस्त में बेंदीगिरी में हुआ था, वहां 13 सवर्णों ने चार हरिजनों को जबरन मैला खिलाया था. इन हरिजनों पर केवल चारा चुराए जाने का आरोप था.

इस वारदात और उसके विरोध से सवर्णों का दशकों पुराना रवैया नहीं बदला है. और इससे पहले कि टत्तूर का मामला ठंडा पड़ जाए एक और हरिजन बाजरप्पा के मामले की रपट भी आ गई. उसे रायचूर में सवर्णों ने मार डाला था क्योंकि उसने एक होटल से एक कप चाय मांगने का साहस किया था.

—अनीता प्रताप टत्तूर में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

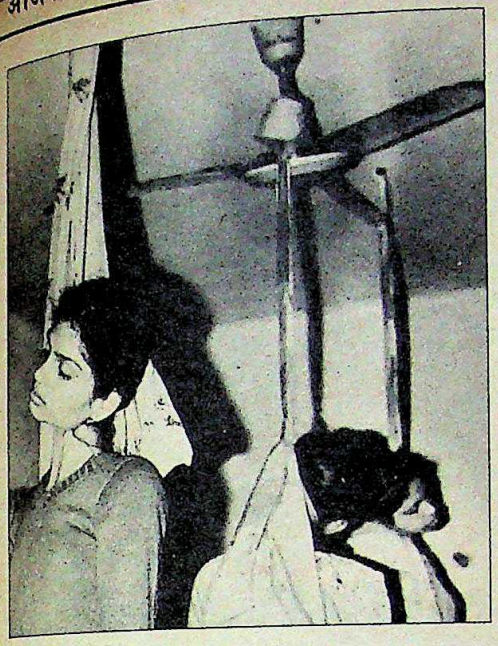

उत्तर प्रदेश

दहेज की बलि

तीन बहनों ने फांसी लगा ली

दहेज का फंदा पिछले पखवाड़े कानपुर के एक मध्यमवर्गीय परिवार पर कसा और उसने तीन बहनों की जान ले ली. दहेज के लोभी दूल्हों के आगे परेड करने के अपमान और अपने घरवालों को दहेज जुटाने में परेशान देखकर पूनम (22), ममता (20) और अलका (18) ने एक साथ फांसी लगा ली.

जीवन बीमा निगम में सहायक प्रशासनिक अधिकारी उनके 50 वर्षीय पिता गया प्रसाद साहु एकदम हतप्रभ हैं. वे सिसकते हुए बताते हैं, "वे हमारा साथ छोड़ गईं. मेरे लिए यह शर्म की बात है....मैं उनकी शादी नहीं कर सका."

पूनम के आठ संभावित दूल्हों और उनके परिवार वालों से शादी की बातचीत चलाने की याद करते हुए साहु ने कहा कि वे उनमें से किसी की भी दहेज की मांग पूरी नहीं कर पाए. चार साल पहले 40,000 रुपए देने को तैयार साहु पिछले दिसंबर में लड़की देखने आए रेलवे के एक क्लर्क को 80,000 रुपए देने पर भी तैयार हो गए थे.

पूनम अपने पिता से कहा करती थी कि शादी के मान-मनौव्वल वाली इस प्रक्रिया में वह अपने को अपमानित महसूस करती है. उसने और दोनों छोटी बहनों ने मां-बाप से

दहेज की ताजा बलिः लाइलाज कोढ़

यहां तक कहा कि वे शादी ही नहीं करना चाहतीं. अवाक् खड़ी अपनी पत्नी की मौजूदगी में साहु बताते हैं, "छोटी लड़कियों ने हाल में कह दिया था कि दीदी को दिखाना बंद कर दीजिए. पर मुझे जरा भर भान नहीं था कि वे ऐसा कर बैठेंगी."

साहु हर महीने 4,000 रुपए कमाते हैं, फिर भी वे संभावित दूल्हों की मांग पूरी करने में असमर्थ थे. वे घर के सभी खर्चों में कटौती करके जितना संभव होता बचाते थे. कानपुर के अपने चार कमरे वाले घर को उन्होंने 400 रुपए किराए पर उठा दिया था और आठ लोगों (पांच बेटियां, एक बेटा और मियां-बीवी) का परिवार कूली बाजार के 60 रुपए भाड़े के मकान में रहता था.

बच्चों की पढ़ाई पर खर्च में उन्होंने कंजूसी नहीं की. एमए करने के बाद पूनम ने हाल ही में स्टेनोग्राफर के कोर्स में दाखिला लिया था. दोनों छोटी बहनें एमए और बीए में पढ़ रही थीं.

इस परिवार के लिए 3 फरवरी दुर्भाग्यपूर्ण था. उस दिन साहु दंपति तीनों छोटे बच्चों को लेकर एक शादी में भाग लेने लखनऊ गए थे. तीनों बहनों ने इन लोगों को सुबह आठ बजे नाश्ता करा दिया था. पर खुद कुछ नहीं लिया. साहु बताते हैं, "हमारे पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया कि हमारे जाने के बाद वे खा लेंगी."

साहु की सास फूलवती वैसे ही घूमने के लिए जब 4.30 बजे शाम को घर आईं तब तक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट चुकी थी. सामने का दरवाजा अंदर से बंद था. पड़ोसियों की मदद से वे घर में घुसीं. उन लोगों ने दरार से बेडरूम में झांका और फिर चीख-पुकार मच गई.

पुलिस बुलाई गई और उसने दरवाजा तोड़ा. तीनों बहनों ने मां की साड़ियों को पंखे और शहतीरों से फंसाकर फांसी लगा ली थी. कमरे की एक मेज पर दो चिट्ठियां पड़ी थीं. एक पर पूनम और ममता के दस्तखत थे और दूसरी पर अलका के. इनमें लिखा था, "प्रिय मम्मी-पापा, हम लोग यह खुद कर रही हैं. कृपया हमें माफ कर दें." लेकिन उन लोगों की ओर से कोई माफीनामा नहीं आया जिनके कारण यह सब घटा. —दिलीप अवस्थी, कानपुर में

गुजरात

वन कटाई विवाद

मुख्यमंत्री के इलाके में जंगल कटे

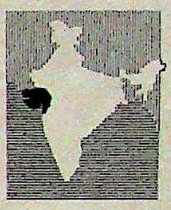

मुख्यमंत्री अमरसिंह चौधरी का शांत विधानसभाई क्षेत्र, सूरत जिले का व्यारा कुछ अप्रत्याशित उत्तेजना महसूस कर रहा है. चौधरी ने पिछले माह के अंत में 'वन बचाओ' को लेकर पदयात्रा की. यह पदयात्रा गुजराती दैनिक 'जय हिंद' में उन पर एक समय व्यारा के हरे वन कटवाने में प्रमुख भूमिका निभाए जाने के आरोप के बाद की गई. उन्होंने अपने खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी की घोषणा की जिससे सभी को आश्चर्य हुआ. समिति में उनके प्रमुख आलोचक और सबसे पहले यह आरोप लगाने वाले झीणाभाई दरजी शामिल हैं. दो अन्य सदस्यों में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (इ) के संयुक्त महासचिव और दरजी के विश्वस्त सी.डी. पटेल और गुजरात जनता पार्टी के अध्यक्ष दलसुख पटेल शामिल हैं.

अमरसिंह चौधरी ने अनुमान लगाया कि यदि दरजी आमंत्रण को ठुकरा देते हैं तो यह उन्हें खुद को निर्दोष साबित करने का

कटाई के बाद व्यारा के जंगल

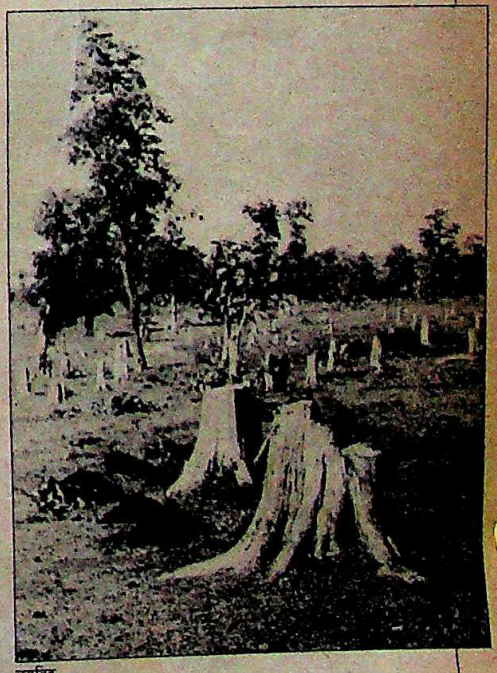

जयहिंद

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

एक अच्छा कारण मिल जाएगा और अगर वह तैयार भी हो जाते हैं तो गलत कार्यों के आरोप सिद्ध करना तो असंभव ही होगा. दूसरी ओर दलसुख पटेल की अमरसिंह चौधरी से अच्छी पटती है.

दरजी ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया. उन्होंने कहा, "मैं काफी समय पहले ही घोषणा कर चुका हूं कि मैं वर्तमान सरकार द्वारा नियुक्त किसी पैनल में नहीं रहूंगा." अमरसिंह चौधरी आत्मसंतुष्टि से कहते हैं, "जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं, यदि वे ही आरोपों की जांच के इच्छुक नहीं हैं तो इस अध्याय को अब समाप्त समझना चाहिए."

असल में जंगल-वाला प्रकरण पुराना है और दैनिक 'जय हिंद' ने केवल इसे पुनर्जीवित किया है. साथ ही इसने विपक्ष को एक कारगर हथियार दे दिया है.

दरजी ने 1986 के अंत में इस विवाद को उठाया. उन्होंने राजीव गांधी को पत्र लिखा कि अमरसिंह चौधरी ने 1985 के विधानसभा चुनावों से पूर्व लकड़ी चोरों को अनियमित पेड़ों की कटाई का लाइसेंस देकर उनका राजनैतिक समर्थन जुटाया.

नवीनतम शिकायत सूरत के इंका नेता महेंद्र दवे की है. दवे ने इसमें मुख्यमंत्री चौधरी के नजदीकी रिश्तेदारों के शामिल होने की बात कही है.

दिलचस्प बात यह है कि सरकारी दस्तावेजों में लकड़ी चोरों में चौधरी के समर्थकों के नहीं बल्कि दरजी के अनुयायियों का नाम दर्ज है.

चौधरी और दरजी: टकराव की राह पर

अमरसिंह चौधरी ने आरोपों को 'अफवाह' बताते हुए कहा, "मेरी दो बहिनों को छोड़कर कोई और लकड़ी जलाता भी नहीं. वे भी वन में रहने के कारण ऐसा करती हैं." पुलिस की वापसी के संबंध में वे कहते हैं कि श्रीमती गांधी की मृत्यु और उसके बाद सांप्रदायिक हिंसा को देखते हुए उसे वापस बुलाना ही पड़ा. वैसे इस विवाद से केवल एक ही तथ्य परे है—वह है ब्यारा वन को जो क्षति पहुंची वह अपूरणीय है.

—उदय महूरकर

आंध्र प्रदेश

विवाद के घेरे में

राज्यपाल ने आफत बुलाई

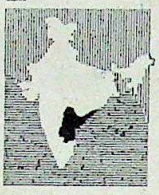

राज्यपाल कुमुदबेन मणिशंकर जोशी तभी से सत्ताधारी तेलुगु देशम की आंख की किरकिरी बनी हुई हैं जब वे नवंबर 1985 में राजभवन में दाखिल हुई थीं. अभी तक उनकी गद्दी को कोई खतरा नहीं पैदा हुआ था. पर पिछले पखवाड़े उनके खिलाफ मुहिम तेज हो उठी. राज्य मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर उनके गणतंत्र दिवस परेड के भाषण के 'सार और अभिप्राय' की निंदा की. कहा गया कि भाषण में उन्होंने 'राज्य की उल्लेखनीय प्रगति को नजरअंदाज' किया है. प्रस्ताव में मुख्यमंत्री नंदमूरि तारक रामराव को अधिकार दिया गया कि वे इस सिलसिले में राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखें.

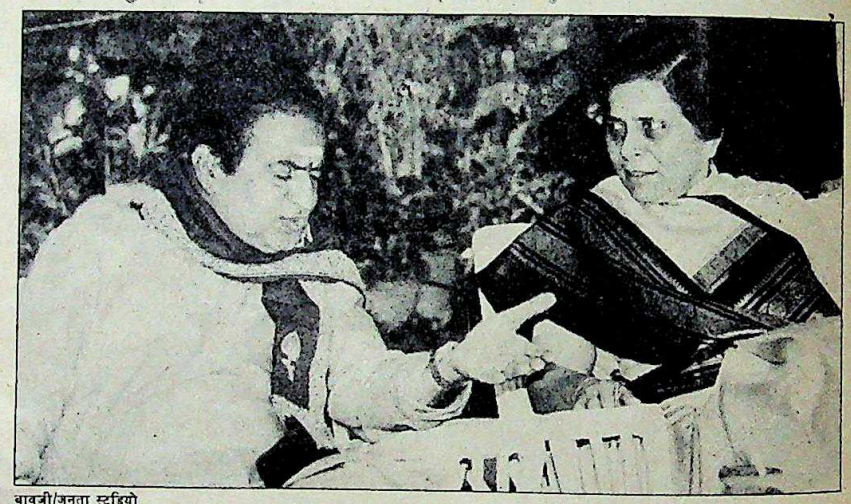

बावजी/जनता स्टूडियो

रामराव के साथ जोशी

हिंदी में दिए 20 मिनट के अपने तात्कालिक भाषण में जोशी ने कहा था, "विकास कार्यक्रमों को लागू करने में भारत सरकार की मदद लिए बगैर कोई भी राज्य तरक्की नहीं कर सकता." उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि केंद्र सरकार विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना पर हर रोज चार करोड़ रुपए खर्च कर रही है. और अनाज के वितरण में 75 पैसे से एक रुपए प्रति किलो तक सबसिडी दे रही है. शायद उनके मन में तेलुगु देशम का यह आरोप घुमड़ रहा था कि केंद्र गैर-इंका राज्यों से भेदभाव बरत रहा है. जोशी ने इसके उत्तर में कई स्थानीय अखबारों को इंटरव्यू दिए. उन्होंने आरोपों का खंडन करते हुए उन्हें 'बकवास' बताया. उन्होंने कहा, "ऐसे आरोपों का जवाब देना भी मैं अपनी शान के खिलाफ समझती हूं."

53 साल की अविवाहित जोशी को तेलुगु देशम एक जल्दबाज औरत की तरह ही मानती रही है. पद संभालते ही उन्होंने प्रदेश के सभी 23 जिलों का दौरा किया. इस तरह उन्होंने अपने पहले के सभी 12 राज्यपालों से ज्यादा सक्रिय होने का रिकार्ड कायम किया. 26 नवंबर 1985 और 30 सितंबर 1987 के बीच वे 108 बार जिलों में गईं और 22 बार प्रदेश के बाहर. रामाराव और उनकी पार्टी के लोगों ने इन दौरों को प्रदेश में इंका के लिए मजबूत आधार तैयार करने की जोशी की कोशिशें माना.

जोशी के गणतंत्र दिवस के भाषण से पार्टी को उन पर आक्षेप करने का मौका हाथ लगा. जब इस भाषण की अतिरंजित टिप्पणियां यहां के अखबारों में छपीं तो कुछ मंत्रियों ने जवाबी हमले की ठान ली. मंत्रिमंडल द्वारा निंदा के प्रस्ताव के बाद एक और प्रस्ताव पास हुआ जो राजभवन के अधिक खर्चों के सिलसिले में था. प्रस्ताव में मांग की गई कि जोशी अपना खर्च घटाकर उसी सीमा में खर्च करें जो अप्रैल 1987 में केंद्र ने तय की थी.

1986-87 के संशोधित बजट अनुमान के मुताबिक जोशी ने 8.53 लाख रुपए अनुबंध भत्ता लिया जबकि उसकी सीमा 54,000 रुपए है. इसी तरह 80,000 रुपए की सीमा होने के बावजूद उन्होंने अपने दौरों पर 5.64 लाख रुपए खर्च किए. मनोरंजन पर 23,000 रुपए के बजाय

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मैं वर्षों प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहा हूँ, तथा अब भी प्रबल हूँ।

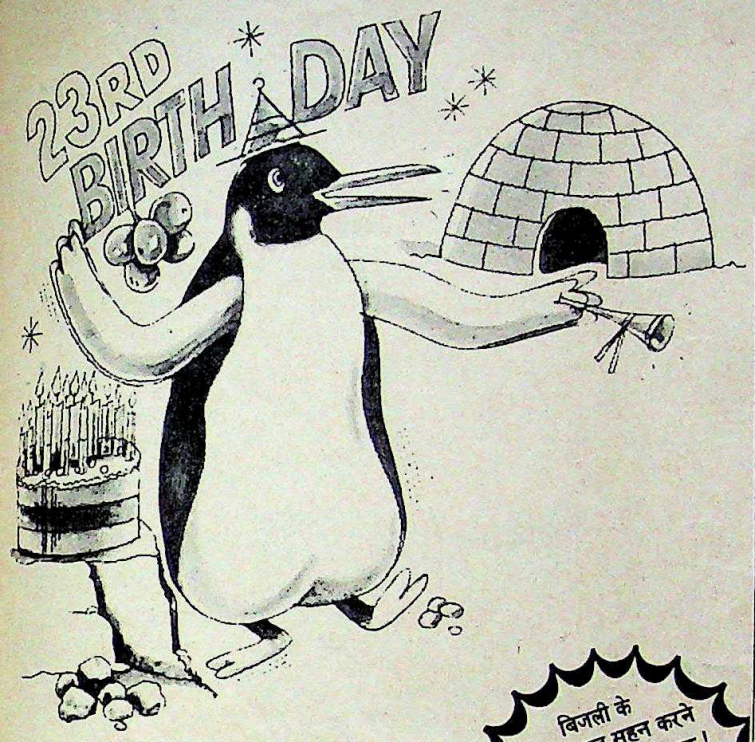

सम्राट पेंग्विन 30 वर्ष या उस से अधिक जीवित रहता है। वह हर वर्ष, प्रजनन तथा दो महीने की अण्ड-सेवन अवधि के दौरान प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों में भी जीवित रहने के लिए उसी बस्ती में आता है।

संदर्भ: बर्ड लाइफ़, लेखक निकोला जे एवं लॉरेन्ज के. प्रकाशक, जी बी पुटमैन्स सन्स, न्यू यार्क, 1974
बर्ड्स ऑफ़ दि वर्ल्ड, लेखक ऑलिवर एल. ऑस्टिन जूनियर प्रकाशक , ऑक्टिमम

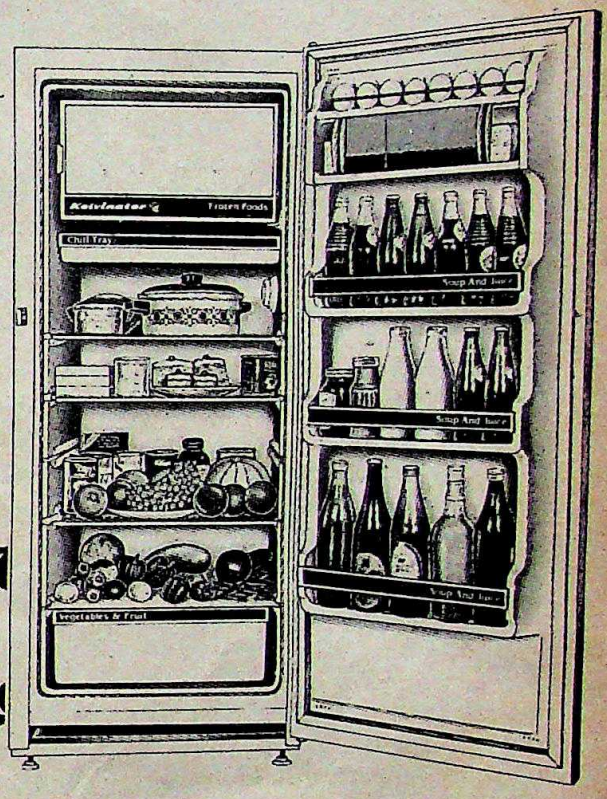

बिजली के उतार-चढ़ाव सहन करने वाला अन्दरूनी प्रोटेक्टर!

वोल्टेज स्टेबिलाइज़र की कोई आवश्यकता नहीं!

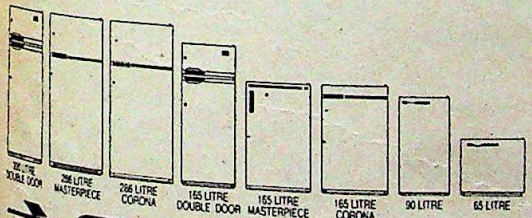

कैल्विनेटर
रेफ़्रिजरेटर
"इसकी ठण्डक...बेमिसाल!"

केल्विनेटर रेफ़्रिजरेटर कभी वृद्ध होता नज़र नहीं आता। वर्षों विश्वसनीय सेवा के पश्चात भी, पहले दिन जैसी क्षमता से कार्य करता है।

इसके लम्बे एवं स्वस्थ जीवन का रहस्य है, इसका मज़बूत हृदय — विश्वविख्यात 'पावर-सेवर' कम्प्रैसर — जो अपनी किफ़ायती विश्वसनीय तथा दोष-रहित सर्विस के लिए प्रसिद्ध है।

बिजली की कम खपत करके यह उच्च व्यापक तापमान में भी उतनी ही तेज़ी से ठंडा करता है। साथ ही यह वोल्टेज के विस्तृत उतार-चढ़ाव सहन करता है।

विशेष खूबियाँ :

* पूर्ण इन्सूलेशन, कैबिनेट तापमान को बेहतर बनाती है।
* मज़बूत ए बी एस लाइनर।
* सर्विस में विश्वसनीय।
* बिजली की खपत में अत्यंत किफ़ायती।
* विशाल स्टोरेज क्षमता।
* टिकाऊ। * सुन्दर एवं सुदृढ़।
* विभिन्न बाहरी फ़िनिश तथा मनभावन अन्दरूनी रंगों में उपलब्ध।
* अनेक मॉडल।

बिक्री एवं सर्विस के लिए :
एक्सपो मशीनरी लिमिटेड
प्रगति टावर, 26 राजिन्द्रा प्लेस नई दिल्ली-110 008.

286 लिटर तथा 165 लिटर मॉडल, डी जी एस एण्ड डी रेट कान्ट्रैक्ट पर भी उपलब्ध

Mutual-4510B/HN

कैल्विनेटर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उनका खर्च 2.60 लाख रुपए रहा. बगीचों पर निर्धारित 10,000 रुपए की जगह उनका खर्च 3.89 लाख रुपए था. इंका नेता कहते हैं कि तेलुगु देशम ये आंकड़े जारी करके राज्यपाल को परेशान करना चाहती है और इस तरह रामराव के खिलाफ सत्ता के दुरुपयोग, कुनबापरस्ती और कुप्रशासन का जो मुकदमा उच्च न्यायालय में चल रहा है, उससे लोगों का ध्यान हटाना चाहती है.

इस बीच जोशी ने अपने खर्चों के सिलसिले में कोई बयान जारी करने या प्रेस से मिलने से इनकार कर दिया है. राजभवन के एक सूत्र का कहना है, "खर्चे इसलिए बढ़े क्योंकि तत्कालीन राष्ट्रपति जैल सिंह निलायम में ठहरने के बजाय अपने पूरे तामझाम के साथ यहां आकर ठहरते थे. और फिर हमने राजभवन में अब खुशबूदार पौधे लगाए हैं, हिरण पार्क बनाया है तथा परिंदे और मधुमक्खियां पालना भी शुरू कर दिया है."

जब मंत्रिमंडल के प्रस्ताव की घोषणा की गई तो जोशी प्रधानमंत्री राजीव गांधी की अगवानी के लिए विशाखापत्तनम गई हुई थीं. हैदराबाद लौटने के बजाय वे राजीव के साथ दिल्ली चली गईं. वहां उन्होंने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आर. वेंकटरामन को इस विवाद की जानकारी दी. राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष बुच्चैया चौधरी गुस्से में कहते हैं, "अगर वे निष्पक्ष संवैधानिक भूमिका निभा रही हैं तो उन्हें इस तरह दिल्ली भागने की क्या जरूरत थी? हमारी पार्टी और जनता को उन पर रत्ती भर विश्वास नहीं." 1983 में सत्ता में आने से लेकर अब तक तेलुगु देशम ने किसी भी राज्यपाल पर विश्वास नहीं किया है.

दिलचस्प बात यह है कि विवाद उस समय खड़ा हुआ जब राज्यपालों की नियुक्ति और उनकी भूमिका पर सरकारिया आयोग की सिफारिशें घोषित की गईं. सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक राज्यपाल का "एक अलग व्यक्तित्व होना चाहिए और उसे स्थानीय राजनीति से करीबी तौर पर नहीं जुड़ना चाहिए." रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि "केंद्र में सरकार चला रहे दल के राजनीतिक को ऐसे राज्य में राज्यपाल नहीं बनाना चाहिए जहां किसी दूसरे दल की सरकार हो." केंद्र और जोशी को इस सलाह पर गौर करना चाहिए. यदि वे ऐसा करते हैं और जोशी को पद से हटा दिया गया तो तेलुगु देशम सरकार को अपने पांच साल के शासन में पांचवां राज्यपाल झेलना होगा.

—अमरनाथ के. मेनन

पंजाब

बदला पैंतरा

केंद्र अब चुनाव के मूड में

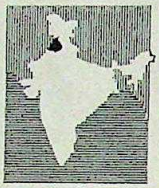

पिछले पखवाड़े राज्यपाल सिद्धार्थ शंकर राय ने अपने बयानों की एकरूपता तोड़ दी. वे कहते रहे थे कि आतंकवाद समाप्त हुए बिना पंजाब में चले आ रहे राष्ट्रपति शासन में कोई तब्दीली जरूरी नहीं है. अचानक उन्हें लगा, "अशांत क्षेत्रों में शांति बहाल करने के लिए एक राजनैतिक पहल आवश्यक है."

यह बदला हुआ पैंतरा केंद्र के इस विश्वास के संकेत के रूप में माना जा सकता है कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन शांति स्थापित करने में विफल हो गया है. सिद्धार्थ शंकर राय ने 'स्थिति की समीक्षा करने के लिए' अकाली नेताओं — संयुक्त अकाली दल के प्रकाश सिंह बादल और अकाली दल (लोंगोवाल) के सुरजीत सिंह बरनाला को निमंत्रण देने प्रारंभ किए. दोनों ही नेताओं ने राज्यपाल का आमंत्रण ठुकरा दिया.

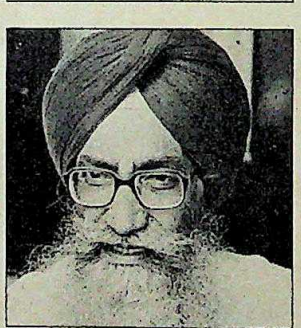

बादल (ऊपर) और बरनाला: चुनाव का विरोध

राष्ट्रपति शासन की असफलता को स्वीकार करने की जगह अकाली नेताओं से चुनाव की मांग कराना, इस न्यौते की मंशा लगती है. ऐसा लगता है कि राज्यपाल को नई दिल्ली से इस तरह के आदेश मिले हैं कि वे राज्य में चुनाव का वातावरण तैयार करें.

प्रकाश सिंह बादल कहते हैं, "राज्यपाल से विचार-विमर्श की क्या आवश्यकता है, जबकि केंद्र को ही सारी बातें तय करनी हैं?" बरनाला की प्रतिक्रिया थी, "राय बेकार के धंधे में लगे हुए हैं, क्योंकि केंद्र पहले से ही इस मसले पर हमारे विचार अच्छी तरह से जानता है."

दोनों नेताओं के जनता में दिए वक्तव्यों के बावजूद उनके दलों ने केंद्र की स्पष्ट होती बदलाव की नीति पर प्रतिक्रिया जाहिर करना प्रारंभ कर दिया है. सामान्य तौर पर चुनावों से पहले प्रारंभ होने वाली विधायकों की सरगर्मी तेज हो गई है. बरनाला दावा करते हैं कि उन्हें 46 विधायकों का समर्थन हासिल है जबकि प्रकाश सिंह बादल के अनुसार उनमें से अधिकतर संयुक्त अकाली दल में शामिल होने के इच्छुक हैं. बादल को उन 22 विधायकों का समर्थन हासिल है जो पिछले विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दलबदल कानून के अंतर्गत अयोग्य करार दिए गए हैं.

आपसी तकरार के अलावा दोनों अकाली नेताओं की अपने सहायकों से अनबन है. अकाली दल (लोंगोवाल) के पूर्व वित्तमंत्री बलवंत सिंह नेतृत्व के सवाल पर बरनाला के खिलाफ हैं. उधर बादल की संयुक्त अकाली विधायक दल के नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह से नाराजगी सिद्धांतों को लेकर है.

बादल अकाली एकता के अपने पुराने प्रस्ताव से भी अब पीछे हट गए हैं. उन्होंने यह प्रस्ताव लगभग एक साल की नजरबंदी से रिहा होने के कुछ समय बाद रखा था. इसका असली मकसद और अधिक विधायकों को लोंगोवाल गुट से तोड़कर उनका समर्थन हासिल करना था. लेकिन जैसे ही उन्होंने अनुभव किया कि अकाली दल (लोंगोवाल) के एक दर्जन से अधिक विधायक अपनी निष्ठा बदलने के लिए तैयार बैठे हैं, उन्होंने इसमें रुचि लेनी छोड़ दी.

फिलहाल बादल देवीलाल और लोकदल (ब) से रिश्ता सुधारने में लगे हैं जिसने हरियाणा में अपने कमजोर प्रतिद्वंद्वियों लोकदल (अ) और कांग्रेस (इ) को परास्त कर विजय हासिल की थी. वे अब कहने लगे हैं कि दोनों अकाली दलों के बीच 'मूल्यों को लेकर मतभेद हैं.' यह बयान उनके पुराने वक्तव्य के बिना अधूरा है कि संयुक्त अकाली दल केंद्र से कारगर ढंग से टक्कर ले सकता है.

अब बादल का मानना है कि 'पंथिक एकता' अकाली एकता से अधिक महत्वपूर्ण है. पूर्व मुख्यमंत्री ने बड़ी चतुराई से नैतिकता को आवश्यकता के अनुरूप ढाल लिया है.

—विपुल मुद्गल

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रघुपति राजीव राजा राम

दूरदर्शन का सीरियल 'रामायण' बेहद लोकप्रिय होने के बावजूद देश की नई पीढ़ी पर जैसा चाहिए वैसा असर नहीं डाल पा रहा. अफसोस तो इस बात का है कि देश की नई पौध को इस प्राचीन महाकाव्य का आधुनिक भारत के साथ कहीं कोई तालमेल बैठता नजर ही नहीं आता. जाहिर है कुछ ऐसा होना चाहिए जो इस पीढ़ी के गले उतर सके. इसीलिए मैंने पटकथा संशोधित कर दी है. और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि दूरदर्शन जल्दी ही अपने राष्ट्रीय प्रसारण में इसे प्रसारित करने लगेगा. मेरे महाकाव्य के मुख्य पात्र राम और सीता नहीं बल्कि राजीव और सोनिया हैं. जरा इस नए सीरियल की एक बानगी देखिए:

दृश्य पहला

एक दरबारी: "हे राजीव, यदि आप अपनी प्रिया सोनिया और उनकी सहेलियों की नज़रे-इनायत हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने शौर्य का बढ़-चढ़कर प्रदर्शन करना होगा. और साबित कर देना होगा कि आपके समान न कोई हुआ और न कोई भविष्य में होगा."

राजीव: "वह कैसे भला? क्या मुझे कोई ऐसा धनुष तोड़ना पड़ेगा, जो कोई और नहीं तोड़ सकता?"

दरबारी: "नहीं, आपको कोई ऐसा कानून तोड़ना पड़ेगा जिसे कोई और न तोड़ सकता हो."

राजीव: "मैं तो पहले ही साम्राज्य के बड़े-से-बड़े कानून को तोड़-मरोड़कर उसकी दुर्गति कर चुका हूं. तुम्हारा क्या ख्याल है सोनिया के पिता अब मेरा सम्मान करने लगेंगे?"

दरबारी: सोनिया के पिता ही नहीं, अब तो दुनिया का हर 'गॉड फादर' आपको प्रशंसा की नजरों से देखने लगेगा..."

दृश्य दूसरा

सोनिया: "हे नाथ, हे नियंता! मैंने आपके 'गुच्ची' (इटली की कंपनी के) जूते सिंहासन पर रखे देखे हैं. वहां भला उन जूतों का क्या काम?"

राजीव: "प्रिये, सोनिया! क्या तुम्हें यह भी नहीं मालूम यह तो हमारी प्राचीन परंपरा है. जब-जब मैं महल छोड़कर जाऊंगा तब-तब ये जूते ही मेरा राज चलाएंगे. तिवारी, नरसिंह राव और बाकी तमाम विदूषकों को श्रद्धापूर्वक इनका नमन करते रहना होगा. और वे इन्हीं के प्रति समर्पित होंगे."

सोनिया: "हे भगवान, आप महल छोड़कर जाएंगे? कहां जाएंगे प्राणेश्वर?"

राजीव: "जंगलों में प्रिये."

सोनिया: (पीले पड़ते हुए) "क्या आपको वनवास मिल गया है?"

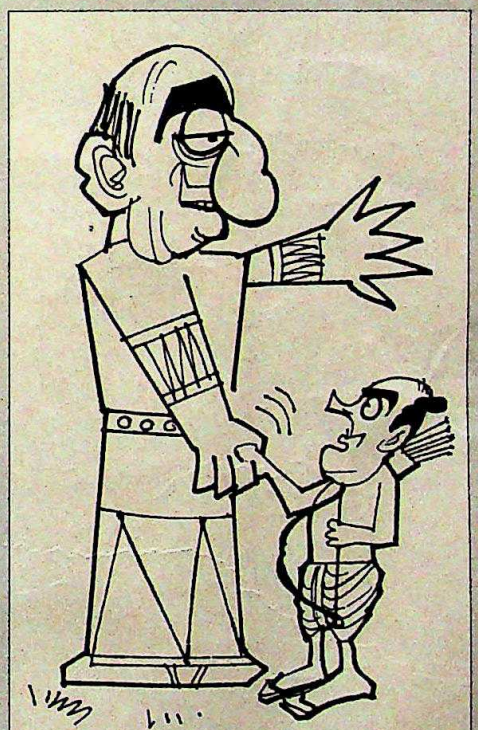

राजीव: "नहीं मूरख! हम तो छुट्टियां मनाने जा रहे हैं सरिस्का, लक्षद्वीप, विदेशों में और भी कई जगहों पर..."

दृश्य तीसरा

सेवक: "मेरे मालिक, श्रीलंका नरेश, महामहिम जय रावण पधार रहे हैं."

राजीव: "उन्हें पूरे सम्मान के साथ अंदर ले आओ सेवक."

जय रावण का प्रवेश: "भारत सम्राट राजीव की जय हो!"

राजीव: "जय हो, हे जय रावण आपकी जय हो! क्या आप ऐलान-ए-जंग करने के लिए पधारे हैं?"

जय रावण: "यह सच नहीं है प्यारे राजीव. हमारे पूर्वज राम और रावण तो हनुमान की बदमाशी की वजह से आपस में उलझ बैठे थे. हनुमान की संतानें एक बार फिर बदमाशी पर उतर आई हैं."

राजीव: "लेकिन जहां तक मैं समझता हूं हे जय रावण, फिलहाल बंदरों की कोई सेना तो आपके साम्राज्य के लिए खतरे का सबब बन नहीं रही है. फिर आपकी समस्या क्या है?"

जय रावण: "हे राजीव, सिर्फ बंदर ही होते तो कोई बात नहीं थी. हालात तो उससे भी कहीं बदतर हैं. हनुमान के बेटों ने चीतों की फौज लेकर हमारे साम्राज्य पर चढ़ाई कर दी है."

राजीव: "तो अब आप बताइए आपकी क्या राय में हमें क्या करना चाहिए जय रावण?"

जय रावण: "हे राजीव! राम और रावण ने जो गलती की थी उसे हम फिर न दुहराएं. आपस में लड़ने के बजाय हम खुलकर दोनों मिलकर हनुमान की सेना का मुकाबला करें."

राजीव: "हे जय रावण, तब तो आप मेरे हाथ तुरंत थाम लें. मेरे लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है. आखिरकार समझौते तो हमेशा से मेरी पसंदीदा चीज रहे हैं. और इसके साथ ही मुझे एक और समझौते का मौका मिल जाएगा."

जय रावण: "आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है प्रभो! रामराज्य खत्म हो और राजीव-राज्य की शुरुआत हो...."

दृश्य धीरे-धीरे ओझल होता जा रहा है, राजीव और जय रावण गर्मजोशी से हाथ मिला रहे हैं और गांधर्व महाविद्यालय के समूहगान गाते कलाकार उभर रहे हैं. वे गा रहे हैं:

"रघुपति राजीव राजा राम
स्नैम प्रोगेती करे काम
ईश्वर अल्लाह तेरे नाम
सबको सबमॅरीन दे भगवान
रघुपति राजीव राजा...."

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मुस्लिम महिला कानून

निगलते बने न उगलते

कानून के विरोधाभासों के कारण तलाकशुदा औरतों की हालत बदतर

लखनऊ के मुंसिफ मजिस्ट्रेट के फैसले से पिछले पखवाड़े विवादास्पद मुस्लिम महिला कानून एक बार फिर सुर्खियों में आ गया. हालांकि यह कानून बनने के बाद लगभग बिसार दिया गया था पर नए या पुराने कानून की जद से बहुत दूर रहने वाली परित्यक्ता या तलाकशुदा मुसलमान औरतों के दिलों में यह शूल-सा चुभता रहा. पुरानी दिल्ली की तंग, संकरी, बदबूदार गलियों में लाचार और बेसहारा जिंदगी जी रही ऐसी बहुत-सी औरतों से वरिष्ठ संवाददाता डेविड देवदास **ने बातचीत की. उनकी रिपोर्ट:**

शाहबानो से लेकर फहमिदा अहमद तक मुस्लिम महिलाओं की हक की लड़ाई लंबी दूरी तय कर चुकी है. पिछले पखवाड़े लखनऊ की एक अदालत द्वारा 28 बरस की तलाकशुदा मुसलमान औरत फहमिदा को उसके खाविंद से गुजर-बसर के लिए एक बड़ी रकम दिलाने की खबर से नारी मुक्ति आंदोलन के कार्यकर्ता विजयी मुद्रा में दिखे. लगा कि अभूतपूर्व विवादों के बीच तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए मई 1986 में बना मुस्लिम महिला कानून आखिर अमल में लाया जाने लगा है. लेकिन मुस्लिम समाज में रूढ़िवादी तत्व अभी भी नाखुश हैं.

नए कानून के अनुसार खाविंद को तलाक के बाद तीन महीने (इद्दत) तक अपनी बीवी की परवरिश का खर्च उठाना होता है. इसके अलावा उसे मेहर की रकम भी (यदि अदा न की गई हो तो) चुकानी पड़ती है. मुसलमानों में शादी के वक्त दूल्हा अपनी दुल्हन को 'मेहर' के तौर पर एक खास रकम देने का वायदा करता है. दहेज के साथ ही दुल्हन को मिले दूसरे तोहफों पर भी बीवी का ही हक मान लिया गया है.

जाहिर है इस कानून से कोई भी खुश नहीं है. इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं सुनवाई के लिए पड़ी हैं. तारा अली बेग और डेनियल लतीफी समेत कई वकीलों और महिला नेताओं ने इसके संवैधानिक औचित्य को ही चुनौती दी है. पश्चिम बंगाल वक्फ बोर्ड की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि तलाकशुदा गरीब औरत के गुजारे की जिम्मेदारी बोर्ड पर नहीं डाली जा सकती. ऐसे कई मामले सुप्रीम कोर्ट और निचली अदालतों में भी चल रहे हैं.

हालांकि लखनऊ की अदालत के फैसले से यह विवाद फिर जीवंत हो उठा है (देखें बॉक्स) पर कई तलाकशुदा गरीब मुसलमान औरतों की हालत जस की तस है. उन्हें न तो नए कानून का फायदा मिल रहा है, न पुराने कानून का. हकीकत तो यह है कि नया कानून बनने के बावजूद कई औरतों की हालत खस्ता ही हुई है.

मुसलमान औरत तमाम तरह की कुर्बानियां देकर खाविंद को खुश रखने के लिए मजबूर होती है क्योंकि आसानी से तलाक मिल जाने का खतरा उस पर मंडराता रहता है. नए कानून ने तलाक देना और भी आसान कर दिया है. हालांकि औरतों की मारपीट समेत उन पर बेरहम अत्याचार कोई नए नहीं हैं और न किसी खास समुदाय तक सीमित हैं लेकिन नए कानून ने मुसलमान मर्दों और उनके परिवार वालों को औरत के शोषण का नया हथियार मुहैया करा दिया है.

अहम बात तो यह है कि भारत में जुबानी तलाक देने की कानूनी आजादी है हालांकि पाकिस्तान समेत दूसरे मुस्लिम देशों में यह प्रथा या तो खत्म कर दी गई है या इसमें सुधार किया गया है. 21 बरस की साफिया का मामला तो अजीब ही है. पिछली गर्मियों में उसे फोन पर ही तलाक दे दिया गया. आज उसे यह भी मालूम नहीं कि वह शादीशुदा है भी या नहीं. क्योंकि जैसे ही

सभी फोटो: भवान सिंह

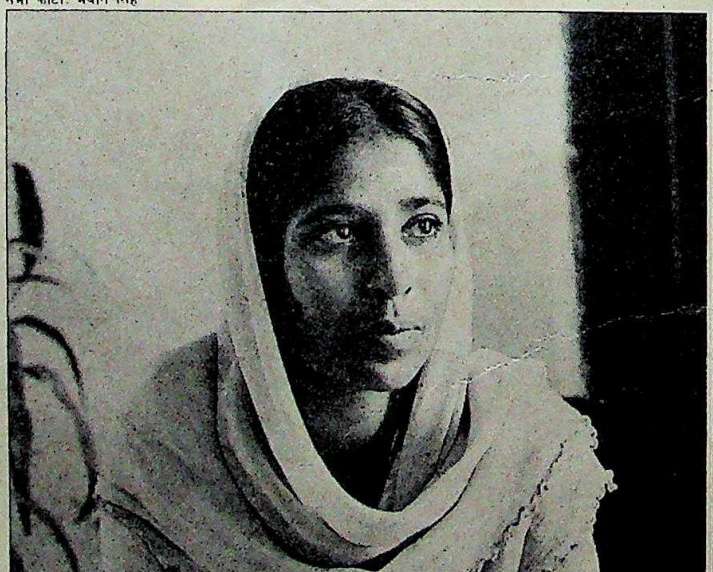

तंग आकर शाहिदा ने तलाक चाहा. खाविंद ने उसे तुरंत छोड़ देने की तैयारी दिखाई बशर्ते कि वह न तो गुजारा भत्ते की मांग करे, न ही तोहफों पर कोई दावा पेश करे. अनजाने में उसने अपने मकान और चार बच्चों पर भी अपना दावा भी छोड़ दिया

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बीस साल की कैसरजहां का बाप नूर मुहम्मद दहेज और मेहर की रकम गंवाने के डर से बेटी को तलाक का मुकदमा नहीं करने दे रहा. बूढ़े ने धमकी दी कि यदि यह रकम वापस न मिली तो वह बेटी के ससुरालवालों को गोली मार देगा

उसने मेहर, दहेज और शादी के दूसरे तोहफे वापस पाने के लिए कदम उठाए तो उसके खाविंद ने फौरन दलील गढ़ी कि फोन पर दिया गया तलाक जायज नहीं था और वह उसे फिर से कबूल कर लेगा.

कानूनी मदद देने वाली संस्थाएं और महिला संगठन हालांकि बेसहारा, तलाकशुदा मुसलमान औरतों की लड़ाई आजकल लड़ने लगे हैं पर यह काम इतना आसान नहीं है. नए कानून के साथ-साथ मुसलमानों में जुबानी तलाक को कानूनी मंजूरी और मर्दों को कई शादियों की छूट होने से मर्दों का पक्ष ही ज्यादा मजबूत हुआ है. कोई मर्द चूंकि दुबारा शादी कर सकता है इसलिए जब तक उसकी बीवी मेहर और दूसरी चीजें छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती वह तलाक जानबूझकर लटके रखने की धमकी भी दे सकता है.

24 साल की शाहिदा का मामला लें. कुछ ही महीने पहले दिल्ली पुलिस के महिला प्रकोष्ठ के बीच-बचाव से वह तलाक हासिल कर सकी. शादी के बाद उठे झंझटों से आजिज आकर उसने तलाक चाहा था. उसे कानूनी सौदे की पेशकश की गई—उसका खाविंद तुरंत तलाक दे देगा बशर्ते कि शाहिदा इकरारनामे में यह लिखकर दे कि वह न तो दुबारा भत्ते की मांग करेगी और न अपने तोहफों पर कोई दावा करेगी. शाहिदा ने जेजाने में ऐसे इकरारनामे पर दस्तखत करके उस मकान पर से भी अपना दावा छोड़ दिया जिसमें वह खाविंद के साथ रहती थी. यह मकान उसका दहेज का सामान बेचने के बाद खरीदा गया था. इनमें सोने के गहने भी थे जो 10 साल पहले शादी के कुछ ही महीने बाद उससे ले लिए गए थे. बेचारी अनपढ़ लड़की को बाद में पता चला कि इकरारनामे में उसके चार बच्चों को पिता के साथ रखने की बात भी लिखवा ली गई है. फिर भी उसने सब्र कर लिया. वह कहती है, "ठीक है, वे उसी के साथ रहें." वह उनका पालन-पोषण भी कैसे कर पाती, उसके पास आमदनी का कोई जरिया तो है ही नहीं.

नए कानून के अनुसार इद्दत के बाद तलाकशुदा औरत के गुजारे की जिम्मेदारी उसके मां-बाप और दूसरे रिश्तेदारों की है. शाहिदा की विधवा मां के लिए अपना गुजारा चलाना ही मुहाल है. कानून में कहा गया है कि अगर रिश्तेदार सहारा न दे पाएं तो स्थानीय वक्फ बोर्ड यह जिम्मेदारी उठाए. पश्चिम बंगाल वक्फ बोर्ड की सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में सवाल उठाया गया है कि तलाकशुदा औरतों की जिम्मेदारी उठाने की हालत में वक्फ बोर्ड हैं भी या नहीं.

नए कानून में यह तय नहीं किया गया है कि क्या सभी मामलों में मेहर लौटाना होगा. मुसलमानों के कुछ तबकों में आम दस्तूर है कि अगर औरत तलाक मांगे तो उसे मेहर की रकम छोड़नी होगी. कुछ औरतों को डर रहता है कि अगर उन्होंने तलाक मांगा तो उन्हें नए कानून के मुताबिक मिलने वाली सुविधाओं से भी हाथ धोना पड़ेगा.

20 वर्षीय कैसरजहां ससुराल में अत्याचार सहने के बाद मायके लौट आई. उसका 66 वर्षीय पिता नूर मुहम्मद गर्भवती बेटी को इस डर से तलाक का मुकदमा दायर नहीं करने देता कि उसने शादी पर बेटी को जो सामान दिया था, कहीं वह उससे भी हाथ न धो बैठे. पर अंदर से वह बहुत नाराज है. बेटी के ससुराल वालों को धमकाने की मुद्रा में तर्जनी उठाकर वह कहता है कि अगर दहेज में दिया गया सोना, चांदी, कपड़े वापस नहीं किए गए तो वह दामाद के पूरे परिवार को गोली से उड़ा देगा. नूर मुहम्मद पुरानी दिल्ली की गलियों में फल बेचकर 300 से 400 रुपए माहवार तक कमा लेता है. अब इसी से उसे कैसर तथा तीन छोटे बच्चों का गुजारा करना है. बेटी के होने वाले बच्चे के बारे में वह कहता है, "कौन जानता है कि वह जिंदा पैदा होगा या मुर्दा!"

दहेज का कोढ़ किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं. लेकिन नए कानून से पैदा हुए खौफ की वजह से मुस्लिम समाज में यह भयावह हद तक पहुंच गया है. दुल्हन या तो मुंहमांगा दहेज लाए या हर वक्त तलाक के साये में जीती रहे.

ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं. 25 वर्षीया फिरोजा बताती है कि ससुराल वालों ने उसे धमकाया कि अगर वह सुखचैन से घर में रहना चाहती है तो अपने 70 वर्षीय गरीब बाप से एक मकान और दुकान खरीदने

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रफीकां का पति उसकी उम्मीदें बनाए रखने के लिए कई चालें चलता रहा है क्योंकि तलाक का मतलब उसका हक लौटाना होगा

लायक पैसा लेकर आए वरना उसे तलाक दे दिया जाएगा. पर इसकी नौबत ही नहीं आई. कुछ महीने पहले डॉक्टरी जांच में उसे तपेदिक की रोगी पाए जाने पर घर से निकाल दिया गया. फिरोजा के मुताबिक ससुराल वाले उसे पीहर छोड़ गए और उसका खाविंद नई बीवी ले आया.

रफीकां की जिंदगी उजड़ गई है. हालांकि वह अभी कमसिन ही है पर अपने कमजोर और झुर्रीदार चेहरे से 40 के आसपास की लगती है. ससुराल और पीहर दोनों ठिकानों से ठुकराई जाकर वह दिल्ली में जामा मस्जिद के पास की भीड़भाड़ भरी गलियों में भीख मांगने को मजबूर हो गई है. सूनी आंखों से दूर कहीं निहारते हुए वह बताती है कि वहां उसे तो आंगन में बिठा दिया जाता है जबकि दूसरी बीवी के लिए गर्मागर्म कचौड़ियां लाई जाती हैं.

अपनी जवां जिंदगी की दास्तां बयां करते-करते कभी उसकी रुआंसी आवाज तीखी भी हो उठती है. उसके अपने परिवार ने ही उसे पागल करार दे रखा है. नए कानून की रोशनी में उस जैसी कुछ औरतें शोषण की दलदल में जा गिरी हैं तो आश्चर्य नहीं कि उनमें से ज्यादातर जहनी और जिस्मानी परेशानियों को झेलते-झेलते सचमुच ही पागल हो उठें.

लखनऊ

नाटकीय शुरुआत

आर.के. गुप्ता

दीक्षितः उत्साहवर्धक फैसला

लखनऊ की मुंसिफ मजिस्ट्रेट रेखा दीक्षित (29) को सपने में भी गुमान न था कि वे चर्चा का केंद्र बन जाएंगी. पर हाल ही में जब उन्होंने विवादास्पद मुस्लिम महिला (तलाक के अधिकार की रक्षा) कानून, 1986 के तहत दो मुकदमों का फैसला सुनाया तो उनकी चर्चा होना स्वाभाविक ही था. दीक्षित की विशेष अदालत ने कानूनी इतिहास में नया अध्याय जोड़ा. नए कानून के तहत निपटाए जाने वाले ये पहले मामले थे. इनमें सुनाए फैसलों से उत्साहित होकर चार और महिलाओं ने मुकदमे दर्ज करा दिए. पिछले अक्तूबर से अदालत को ऐसी 15 शिकायतें मिली हैं.

इन दोनों मामलों में तलाक लेने वाले पतियों को निर्देश दिया गया है कि वे मेहर की रकम और वे सारी चीजें और तोहफे लौटा दें जो उन्हें भेंट में दिए गए थे. इसके अलावा उन्हें तलाकशुदा बीवियों को इद्दत के तीन महीनों का गुजारा भत्ता देने का भी आदेश दिया गया. एक मामले में प्रतिवादी से कहा गया कि वह कानून के मुताबिक अपनी पूर्व पत्नी के लिए 'जिंदगी गुजारने का उचित और सही इंतजाम' करे.

मुस्लिम संगठनों ने इन फैसलों पर खुलेआम तो कोई टिप्पणी नहीं की है पर उनमें बेचैनी के संकेत हैं. एक फैसले को तो स्थानीय वकील कमरयाब जिलानी ने उसी अदालत में चुनौती भी दी है. कमरयाब कहते हैं, "मैंने पति की तरफ से इस फैसले को चुनौती दी है क्योंकि अदालत ने उसकी सुनवाई ही नहीं की." यह मामला फहमिदा अहमद का था. शादी के पांच साल बाद उसे नौसेना अधिकारी शफात अहमद ने अगस्त 1987 में तलाक दे दिया था. फहमिदा चाहती थी कि अदालत उसे पूर्व पति से अपना जीवन स्तर बनाए रखने के लिए उचित इंतजाम के बतौर 45,000 रुपए (उसे 30,000 हजार रुपए देने का निर्देश हुआ); इद्दत की अवधि के 1000 रुपए प्रतिमाह और मेहर के 52,000 रुपए दिलवाए. इसके अलावा वह उससे 2.10 लाख रुपए से भी ज्यादा के तोहफे वापिस मांग रही थी. अदालत ने उसकी यह मांग भी मान ली. इस पर उसे कुल मिलाकर 2.95 लाख रुपए दिलाने का निर्देश दिया गया.

14 जनवरी को सुनाए गए दूसरे फैसले में अलीगढ़ के मोहम्मद खालिद को निर्देश दिया गया कि वह अपनी तलाकशुदा बीवी शाबिदा खातून (35) को इद्दत की अवधि का डेढ़ हजार रुपए गुजारा खर्चा और मेहर के 11,000 रुपए दे. इसके अलावा उसे 68,980 रुपए मूल्य के तोहफे व दूसरी चीजें लौटाने को भी कहा गया.

मगर दीक्षित कहती हैं, "मैं तलाक को चुनौती देने वाली किसी भी याचिका पर विचार करूंगी और अगर जरूरी हुआ तो प्रतिवादी की बात भी सुनूंगी."

अपनी इस चर्चा से परेशान होकर वे कहती हैं, "मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि दोनों फैसले इतने महत्वपूर्ण होंगे. इसी महीने अपने एक सहयोगी से शादी रचाने जा रही दीक्षित इस बात को लेकर भी चिंतित हैं कि मामले को मुस्लिम कट्टरवादी संगठन तूल दे रहे हैं. वे कहती हैं, "अब मुझे दबाव पड़ने का एहसास हो रहा है. मैंने वही किया जो कानून कहता है." किसी भी कैरियर की शुरुआत इससे ज्यादा नाटकीय और बढ़िया क्या हो सकती है.

—दिलीप अवस्थी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कार्यशाला यानी झगड़े का मंच

गुजरात में हाल ही में इंका की सेमीनार-नुमा कार्यशालाओं ने पार्टी की छवि को निखारा है या धूमिल किया यह एक दिलचस्प सवाल हो सकता है. पार्टी अध्यक्ष राजीव गांधी के आदेश पर चलाई जाने वाली ये कार्यशालाएं इंका के अंदर हावी गुटों के लिए सुविधाजनक मंच बन गए हैं. मसलन राजकोट की कार्यशाला

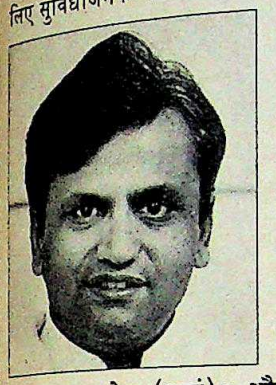

पटेल (बाएं); और चौधरी: टकराव

में मुख्यमंत्री अमर सिह चौधरी ने शुरुआत ही प्रदेश पार्टी संगठन पर हमले से की जिसका नेतृत्व अहमद पटेल करते हैं. उन्होंने राज्य इंका नेताओं को पीठ में छुरा घोंपने वाला करार देते हुए राज्य सरकार के साथ सहयोग न करने का आरोप लगाया.

चौधरी विरोधी खेमा भी पीछे नहीं रहा. दूसरे दिन जब पटेल का भाषण देने का नंबर आया, तब उन्होंने मुख्यमंत्री का नाम न लेते हुए आरोप लगाया कि मंच का उपयोग पार्टी कार्यकर्ताओं की छवि धूमिल करने के लिए किया जा रहा है. उन्होंने राज्य सरकार पर मुद्दे से निबटने में अक्षमता और गुटों के आपसी विवाद को बेवजह तूल देने के आरोप भी लगाए.

बडोदरा में भी स्थिति कोई भिन्न नहीं रही. वहां पटेल की आलोचना करते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि पार्टी में लोकतंत्र नहीं रह गया है. फिर भी चौधरी कहते हैं, "कार्यशालाओं से पार्टी को फायदा हुआ." सूरत में चौधरी के समर्थक कार्यशाला से दूर ही रहे.

कार्बाइड का अड़ियल रुख

पिछले पखवाड़े भोपाल की एक अदालत ने हांगकांग के यूनियन कार्बाइड (यूसीई) को एक सम्मन की अवहेलना करने पर 'कारण बताओ' नोटिस जारी किया. यह सम्मन उस मुकदमे के सिलसिले में जारी किया गया था जो सीबीआई ने गैस रिसाव के कारण नरसंहार के मामले में यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन और उसकी एशियाई शाखा पर दायर कर रखा है. दोनों ही कंपनियां 4 फरवरी को मामले की पहली सुनवाई के दिन भोपाल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में हाजिर नहीं हो पाई थीं.

तीन सालों की छानबीन के बाद सीबीआई ने यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन, यूसीई, यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन इंडिया लिमिटेड और एंडरसन सहित कार्बाइड के नौ अधिकारियों पर मानव हत्या और कई लोगों को अपंग करने का आरोप लगाया है.

यूनियन कार्बाइड इस बात पर अड़ी है कि भोपाल गैस त्रासदी कंपनी के एक असंतुष्ट कर्मचारी की खुराफात है. और भारत सरकार इस तथ्य को स्वीकारने की राजनैतिक हिम्मत नहीं जुटा पाई. अब जबकि इस बहुराष्ट्रीय कंपनी के प्रबंधकों ने भारतीय अदालतों की सजा मानने से इनकार कर दिया है, न तो वादी और न ही अदालत की समझ में आ रहा है कि आगे क्या किया जाए.

आईपीएस वालों की नाराजगी

कर्नाटक में आईएएस अधिकारियों के प्रति 110 आईपीएस अधिकारियों की नाराजगी बढ़ती जा रही है. आईपीएस अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल पिछले पखवाड़े मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े से मिला. उसने अपनी पदोन्नतियों, तबादलों और आईएएस अधिकारियों की तुलना में समान वेतन की मांग रखी. उनकी मुख्य आपत्ति यह थी कि वे तो अक्सर उप-महानिरीक्षक (डीआईजी) के पद तक पहुंचकर अटक जाते हैं जबकि आईएएस ऊपर की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं, भले ही इसके लिए नए पद बनाने पड़ते हों.

दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तो यह है कि दूसरे राज्यों में नियुक्त उनसे कनिष्ठ अधिकारी ऊंचे पदों पर पहुंच रहे हैं. उदाहरण के लिए केरल में नियुक्त 1963 बैच के आईपीएस अधिकारी महानिरीक्षक (आईजी) बन गए हैं लेकिन कर्नाटक में नियुक्त 1962 के बैच के चार आईपीएस अधिकारी अभी भी डीआईजी ही हैं.

आईपीएस अधिकारियों की नाराजगी इस बात पर भी है कि किसी आईपीएस अधिकारी द्वारा संभाले जाने वाले विशेष सचिव (गृह) के पद का दर्जा आईजी से घटाकर डीआईजी का कर दिया गया है. वैसे, सी.जे. आनंदन इस पद पर उस समय नियुक्त किए गए जब उन्हें आईजी बनाया जाना था. इसके पहले इस पद का दर्जा एक आईएएस अधिकारी की सुविधा के लिए बढ़ा दिया गया था. उन्हें मंत्रियों के करीब होने का पुरस्कार मिलता ही है.

माफिया की चुनौती

धनबाद के छह माफिया नेताओं का बहु-चर्चित मुकदमा पिछले पखवाड़े एक तमाशा बन गया. हथियारबंद व्यक्तियों ने दो प्रमुख चश्मदीद गवाहों की गोली मारकर हत्या कर दी. हत्यारों ने 1 फरवरी को राष्ट्रीय कोयलरी मजदूर संघ (आरसीएमयू) के केंद्रीय दफ्तर में घुसकर संगठन के तीन नेताओं की हत्या कर दी और पांच लोगों को घायल कर दिया.

कृष्ण मुरारी किशन

सूर्यदेव सिंह (बीच में)

संदेह तुरंत जनता पार्टी के विधायक और माफिया सरगना सूर्यदेव सिंह पर गया. वे कोयला खदान क्षेत्र के मजदूर संघों के सबसे सशक्त नेता हैं. उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ और न्यायिक अधिकारी ने उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया. बिलकुल फिल्मी अंदाज में वे धनबाद पहुंचे और अदालत में यह कहते हुए आत्मसमर्पण कर दिया कि उन्हें झूठमूठ ही फंसाया जा रहा है.

इन हत्याओं से धनबाद में माफिया के विरुद्ध जंग छेड़े बिहार के मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे को एक और धक्का लगा है. पिछले वर्ष ही उन्होंने माफिया नेताओं के विरुद्ध चल रहे आपराधिक मामलों को फिर शुरू करने का आदेश दिया था. लेकिन यह कार्रवाई उनको उल्टी ही पड़ी. उनकी मजदूर नेता की छवि को भी गहरा आघात लगा है.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

श्रीलंका

वक्त बहुत कम है

नई दीर्घकालिक संधि के प्रस्ताव पर भारत की सतर्कता

श्रीलंका के राजनीतिशास्त्री राल्फ बुल्जेंस ने अपनी नवीनतम पुस्तक 'विंडोज़ ऑन इंडिया' में लिखा है, "भारत और श्रीलंका ऐसे पति-पत्नी की तरह हैं, जो शादी भी कर सकते हैं और तलाक भी ले सकते हैं लेकिन कभी एक-दूसरे से अलग नहीं हो सकते." भारत-श्रीलंका संबंधों की इससे सटीक व्याख्या नहीं हो सकती. बुल्जेंस इंदिरा गांधी के घनिष्ठ मित्र भी रहे हैं. पिछली जुलाई में दोनों देशों के बीच हुए गठजोड़ का जोश अब ठंडा पड़ चला है, इसलिए इस पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत महसूस की जा रही है.

दोनों देशों के बीच अधिकारिक बातचीत के लिए भारत के दौरे पर आए श्रीलंकाई राष्ट्रपति जूनियस जयवर्द्धने ने यों तो अपना ज्यादा वक्त खजुराहो और भरतपुर में सैरसपाटे में ही बिताया. लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत-श्रीलंका समझौते की उनके अपने देश में खासी भद्द हो रही है. इसलिए वे भारत के साथ लंबी अवधि की मैत्री संधि के लिए उत्सुक हैं, ताकि अपने घर में उनकी इज्जत बची रह सके और भारत के हाथों बिकने का कलंक भी मिटे.

संधि का यह प्रस्ताव महत्वपूर्ण वक्त पर किया गया है. 1988 जयवर्द्धने के लिए निर्णायक वर्ष साबित होने वाला है. उनकी सरकार ने घोषणा की है कि प्रांतीय परिषदों के महत्वपूर्ण चुनाव इस वर्ष मार्च या अप्रैल में होंगे. फिर, दस वर्ष में पहली बार आम चुनाव और तब राष्ट्रपति का चुनाव.

श्रीलंका की ओर से इस तरह की कोई पेशकश होगी, इसकी आशंका तो थी लेकिन इस संधि-प्रस्ताव के कारण भारत के सामने कुछ नाजुक कूटनीतिक समस्याएं आ खड़ी

प्रभात पंजियार

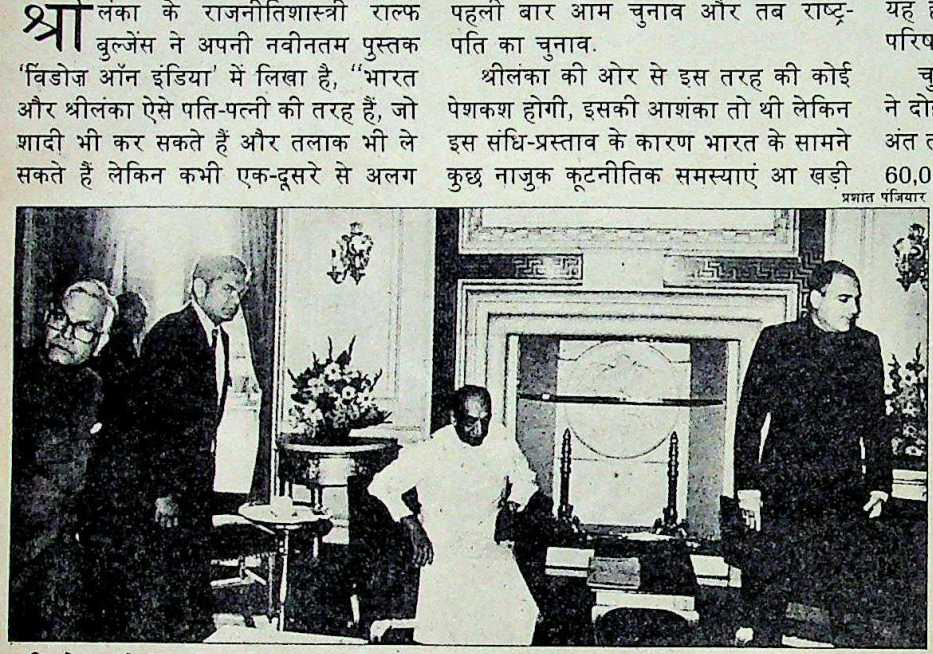

(दाएं से) राजीव, जयवर्द्धने, अतुलतमुदाली और नटवर सिंह

हुई हैं. विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की नीति जयवर्द्धने को पूर्ण समर्थन देने की ही लगती है. लेकिन एक बार मुंह जला चुकने के बाद भारत फूंक-फूंककर पीने की नीति पर चलता दिख रहा है. किसी भी व्यापक संधि के बंधन में बंधने से पहले वह इसकी बारीकी से जांच कर लेना चाहता है.

विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है, "हम सैद्धांतिक तौर पर संधि के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमारी चिंता यह है कि नई संधि के चलते जुलाई में हुए समझौते की कोई व्यवस्था कमजोर न हो."

उनकी यह चिंता स्वाभाविक ही है. इस समझौते की शर्तों की बारीकियों ने ही श्रीलंका को भारत से इस संधि की पेशकश करने को मजबूर किया है. श्रीलंका में समझौते का विरोध करने वाले लोग भी बार-बार यही दोहराते हैं कि राजीव गांधी और जयवर्द्धने के बीच हुए लंबे पत्र-व्यवहार में, जो कि बाद में समझौते का आधार बना, आपसी 'लेन-देन' का तत्व गायब दिखता है. समझौते का मुख्य आधार राजीव गांधी के एक पत्र के ये शब्द हैं, "किसी और देश को श्रीलंका के त्रिंकोमली या किसी दूसरे बंदरगाह के सैनिक इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी जाएगी जिससे भारतीय हितों को चोट पहुंचती हो..." सिंहलियों का मानना है कि भारत को भी इस भावना का सही प्रतिदान देना चाहिए.

भारतीय विदेश मंत्रालय की नीति अब यह है कि संधि प्रस्ताव पर वार्ता प्रांतीय परिषदों के चुनावों तक टाली जाए.

चुनाव संपन्न हो जाएं इसके लिए भारत ने दोहरी रणनीति बनाई है. इस पखवाड़े के अंत तक श्रीलंका में शांति सैनिकों की संख्या 60,000 हो जाएगी. सेना का एक अतिरिक्त ब्रिगेड जयवर्द्धने के दिल्ली पहुंचने से कुछ ही पहले श्रीलंका के पूर्वी प्रांत में पहुंच चुका था. इसके अलावा कोलंबो में भारत के उच्चायुक्त जे.एन. दीक्षित ने जाफना और बट्टीकलोआ में स्थानीय नागरिकों की समितियों और प्रमुख नागरिकों से बातचीत कर उनसे चुनावों में शरीक होने का आग्रह किया है. यदि तमिल चीते चुनावों का बहिष्कार करते हैं तो उनकी वैधता पर ही चिन्ह लग जाएंगे. और यदि वे अब निष्क्रिय रहकर चुनाव के दौरान सिर उठा लेते हैं तब भी समस्या खड़ी हो जाएगी क्योंकि उनमें अभी भी चुनाव में अड़चन डालने का माद्दा है.

इसीलिए भारत ने हाल की बातचीत के दौरान जयवर्द्धने को इस बात के लिए तैयार कर लिया है कि तमिलों को समझौते के तहत कुछ अतिरिक्त रियायतें दे देने से चुनाव के दौरान उनका समर्थन हासिल करने में सहायता मिलेगी. श्रीलंका सरकार इस पर विचार के लिए राजी हो गई है.

एक उच्चस्तरीय सूत्र के अनुसार श्रीलंका सरकार तमिल चीतों से एक गुप्त समझौते के लिए तैयार हो गई है. जिसके अंतर्गत तमिल चीतों को उत्तरी प्रांत में कुछ राजनैतिक अधिकार देने का प्रस्ताव रखा है बशर्ते वे पूर्वी प्रांत पर से अपना दावा बिलकुल छोड़ दें. भारतीय शांति सेना पहले ही उत्तरी प्रांत से चीतों को बेदखल कर चुकी है, और अब पूर्व में भी उसके बढ़ते दबाव के कारण शायद तमिल चीते इस समझौते के लिए राजी हो जाएंगे, कम-से-कम भारत और श्रीलंका सरकार तो यही उम्मीद लगाए बैठी है. देखना यह है कि तमिल चीते अपना तेवर बदल पाते हैं या नहीं.

—दिलीप बॉब

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पी.सी. अलेक्जेंडर

'हालात का जायजा लूंगा'

लंदन में भारतीय उच्चायुक्त पी.सी. अलेक्जेंडर के बारे में करीब तीन माह से चर्चा थी कि उन्हें कर्नाटक या जम्मू-कश्मीर का राज्यपाल बनाया जा रहा है. लेकिन उन्हें तमिलनाडु का राज्यपाल बनाए जाने से बहुतों को आश्चर्य हुआ. घोषणा होते ही उन्हें कई विदाई पार्टियां दी गईं. ब्रिटिश समाचार माध्यम की ओर से भी उनके इंटरव्यू के लिए अनेक अनुरोध आए, जिसके साथ 67 वर्षीय उच्चायुक्त की नोक-झोंक होती रही है.

भारत रवाना होने से एक दिन पहले अलेक्जेंडर ने ब्रिटेन में अपने कार्यकाल और आगामी जिम्मेदारी के बारे में लंदन संवाददाता **रमेश चंद्रन** *से बातचीत की. लेकिन तमिलनाडु के पूर्व राज्यपाल एस.एल. खुराना की विवादास्पद भूमिका के बारे में उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. बातचीत के कुछ अंश:*

• तीन साल के कार्यकाल के बाद ब्रिटेन छोड़ते हुए आपको कैसा लग रहा है?

मन में एक संतोष का भाव है. हमारे आपसी संबंध खासे बेहतर हुए हैं. जब मेरी नियुक्ति हुई थी तो यहां के भारतीयों में बहुत तनाव था. राष्ट्रवादी सिखों का हौसला भी पस्त था. इन सिखों पर अलगाववादियों ने कातिलाना हमले भी किए. लोगों में यह एहसास था कि गोरे हमारी भावनाओं को नहीं समझते. मैंने लगातार कोशिश की वे हमारी भावना को समझें.

• कंजर्वेटिव सरकार क्या इसके प्रति सचमुच चिंतित है?

मुझे विश्वास है कि उन्हें ऐसी चिंता है. जब भी कोई घटना हुई या किसी भारतीय पर हमला हुआ तो मैंने अधिकारियों के बजाय इस मुद्दे पर सीधे गृह सचिव या विदेश सचिव से बात की. और उन्होंने भी बहुत सकारात्मक रवैया अपनाया. उन्हें एहसास हुआ लगता है कि पंजाब में उग्रवादियों को पैसा या हथियार भेजने और शह देने का मतलब भारत जैसे मित्र लोकतांत्रिक देश में अस्थिरता फैलाना है.

• लेकिन इसे रोक पाने की हालत में वे नहीं लगते, मसलन चोरी-छिपे पंजाब में पैसा भेजना?

इसे शायद वे रोक भी नहीं सकते. पर अगर वे उन जाने-पहचाने लोगों के खिलाफ कदम उठाएं जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं तो इससे रोकथाम हो सकती है.

• भारत के प्रति ब्रिटिश लोगों के आकर्षण के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है इसका क्या आधार है?

ब्रिटेन सबसे अधिक संख्या में पर्यटक भारत भेजता है. ब्रिटिश राज की यादें बस पुरानी पीढ़ी तक ही सीमित रह गई हैं. नई पीढ़ी की रुचि आधुनिक भारत के साथ साथ हमारी प्राचीन संस्कृति में भी है.

> "लोग द्रमुक को चुनते हैं तो हम जनमत का ही आदर करेंगे. राज्यपाल संवैधानिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है, उसमें रुकावट नहीं डालता"

• ब्रिटिश समाचार माध्यम में क्या हमारे देश को उचित स्थान मिलता है?

कुल मिलाकर मैं समझता हूं कि भारत को ठीक जगह दी जाती है. लेकिन कुछ ऐसे टीवी कार्यक्रम जरूर हैं जो एकपक्षीय हैं. उनकी नासमझी देखकर मुझे अफसोस होता है. मसलन निजी शादियों के खर्चीलेपन को लेकर बहुत कुछ दिखाया गया.

• भारत और राजीव गांधी पर बीबीसी के हाल के पैनोरमा कार्यक्रम ने जैसे किसी दुखती रग को छू लिया हो. आपने इस पर कड़ा विरोध भी प्रकट किया था. उसमें ऐसी क्या आपत्तिजनक बात थी?

असली भारत के प्रति इसमें समझ का नितांत अभाव था. कुछ ब्रिटिश लोगों ने भी विरोध जताया. वे भारत की इस तरह खिल्ली उड़ाए जाने से नाराज़ थे. कार्यक्रम में देश की वैज्ञानिक और टैक्नोलॉजिकल प्रगति के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया था.

• तमिलनाडु में राजनीतिक संकट के समय राज्यपाल खुराना के क्रियाकलापों को लेकर काफी आलोचना हुई है?

मैं इस बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता.

• क्या आपने इस संकट को अलग तरह से निबटाया होता?

मेरे पास सारे तथ्य नहीं हैं. पहले मैं वहां जाकर सारे हालात का जायजा लूंगा.

• राज्यपाल के रूप में आप सबसे पहले क्या कदम उठाएंगे?

मैं चुनाव के लिए सारी तैयारियां करूंगा ताकि संवैधानिक प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाया जा सके.

• अगर निष्पक्ष चुनाव हों तो द्रमुक जीत सकती है?

अगर लोग द्रमुक को चुनते हैं तो निश्चय ही हम जनता के फैसले का आदर करेंगे. राज्यपाल का काम संवैधानिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है, उसमें रुकावट डालना नहीं.

• आप श्रीमती गांधी और राजीव गांधी के बहुत निकट रहे हैं. इस निकटता का आपको कोई लाभ हुआ है?

यह मेरे लिए सौभाग्य की बात रही है. लेकिन मुझे उम्मीद है कि कोई भी मुझ पर नाजायज फायदा उठाने का आरोप नहीं लगाएगा. श्रीमती गांधी और बाद में राजीव गांधी के साथ मैंने जितने साल काम किया वे मेरे सबसे बेहतरीन साल रहे.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

एक व्यापारिक निर्णय —लिनोलियम

दीवार से दीवार तक कारपेट ? पी वी सी फ्लोरिंग ? या फिर लिनोलियम ? एक व्यापारिक निर्णय लें । लिनोलियम बिछाएं । बिछाने व रख-रखाव में बेहद आसान । प्राकृत्तिक द्रव्यों से निर्मित लिनोलियम स्वच्छ व स्वास्थ्यकर है । टिकाऊ होने के साथ-साथ ध्वनिरोधक भी । एक ही पोंछे में चमक उठे और वर्षों तक नया ही नज़र आए । आकर्षक डिज़ाइनों, रंगों व मोटाई के अदभुत संगम में से अपने मनपसंद के फ़र्श-बिछावन चुनिए ।

लिनोलियम

एक शानदार बहु-उपयोगी फ़र्श-बिछावन

इण्डिया लिनोलियम्स लिमिटेड

९/१, आर. एन. मुखर्जी रोड, कलकत्ता-७०० ००१

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

CC/IL-3/87 HIN

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जेनेलेक पर जोर-आजमाइश

वैसे कृष्णकुमार मोदी ने जेनेलेक के अपने विवादास्पद शेयरों की खरीद को कंपनी कानून बोर्ड द्वारा मान्यता न देने के फैसले के खिलाफ अदालत में अपील कर रखी है पर इस बात की संभावना भी बताई जा रही है कि वे अब इस कंपनी (जिसके पास पहले काफी पूंजी थी और जिसके शेयर अभी काफी गिर गए हैं) में कम दिलचस्पी ले रहे हैं. इस बीच छाबरिया बंधु और सुदर्शन कुमार बिड़ला जैसे कंपनियों पर कब्जा करने वाले लोग इसमें दिलचस्पी लेने लगे हैं. हो सकता है कि जल्दी ही कंपनी के खरीदार बदल जाएं. कहा जाता है कि बिड़ला और छाबरिया जेनेलेक की मूल कंपनी जीईसी को भी खरीदने के इच्छुक हैं.

तू डाल-डाल, मैं पात-पात

फिक्की और एसोचैम के बीच मूंछ की लड़ाई ने नया रूप ले लिया है. दोनों ने ही अब सरकार का आशीर्वाद पाने के लिए उसकी आलोचना कम कर दी जिससे सरकार की कृपादृष्टि उनसे दूर न हो जाए. जब सरकार ने पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी तो फिक्की ने उम्मीद के अनुसार ही इसकी आलोचना की. पर एसोचैम ने इसकी तारीफ करके आर्थिक पंडितों को अचंभे में डाल दिया. जब इस्पात की कीमत बढ़ाने का फैसला हुआ तो एसोचैम तो चुप ही रहा, फिक्की ने भी चुप्पी साध ली. वित्त मंत्रालय के एक बड़े अधिकारी ने फिक्की के एक पदाधिकारी से कहा कि एसोचैम सरकार के प्रति अधिक बेहतर रुख दिखा रहा है और फिक्की को इशारा समझने में देर नहीं लगी.

जापानी मुश्किलें

अगर जापान मे गठबंधन करने वाली भारतीय कंपनियां (कच्चे माल या पुर्जे मंगाने के मामले में) येन की कीमत बढ़ने से मुश्किल महसूस कर रही हैं तो जापान को भी इसी कारण मे भारत या दूसरे देशों में अपना सामान निर्यात करने में मुश्किल हो रही है. अब जापानी कंपनियां विदेशों में अपने कारखाने लगाना चाहती हैं और इस मामले में थाईलैंड उनका सबसे पंसदीदा देश है पर भारत में भी कारखाने लगाने पर विचार चल रहा है. इस मामले में सुमितोमो (जिसने मद्रास एक्सपोर्ट जोन में कपड़े का कारखाना लगाया है और निवेश के और अवसर तलाश रही है), मोनी और दूसरी कंपनियों के नाम सामने आ रहे हैं.

जोखिम भरे शेयर

विदेशी गठबंधन का ढोल पीटते हुए शेयर बाजार में उतरने वाली कंपनियां निवेशकों पर रौब डालने में नाकाम रही हैं. मार्केटिंग ऐंड बिजनेस एसोसिएट्स की सहयोगी 'सिच रिसर्च सर्विस' द्वारा तीन महीने तक 20 शहरों के सर्वेक्षण से ये नतीजे सामने आए हैं. इस एजेंसी ने मर्चेंट बैंकों के एक समूह के लिए 2500 रुपए मासिक आय से ऊपर वाले 6000 से ज्यादा लोगों का सर्वेक्षण किया, जिनमें से दो-तिहाई निवेशक थे. एक और प्रमुख निष्कर्ष था : कम ही लोग यूनिट ट्रस्ट के मास्टर शेयर के बारे में जानते थे जबकि अधिकांश को इंदिरा विकास पत्र की जानकारी थी. सरकारी उपक्रमों के बांड में पैसा लगाना सबसे कम पसंद किया जाता है. शेयर बाजार के फिर से उभरने की एक उम्मीद है कि निवेश न करने वाले लोग दूसरे वित्तीय संसाधनों में पूंजी लगाते हैं क्योंकि उन्हें शेयर बाजार की पेचीदगियों का पता नहीं होता. थोड़ी शिक्षा से ये लोग शायद शेयर बाजार की ओर ध्यान दें.

आयात पर लड़ाई

सीमा शुल्क में वृद्धि और आयात में कड़ाई बढ़ सकती है. भुगतान संतुलन के मामले में योजना आयोग के निष्कर्षों से यही लगता है. सातवीं योजना की मध्यकालीन समीक्षा में आयोग ने कहा है कि भुगतान संतुलन में मुश्किल होगी और घाटा पहले के अनुमानों (चार्ट देखें) को पार कर जाएगा.

सातवीं योजना के अंत तक निर्यात की वार्षिक वृद्धि दर के लक्ष्य

चार्ट: बी के शर्मा

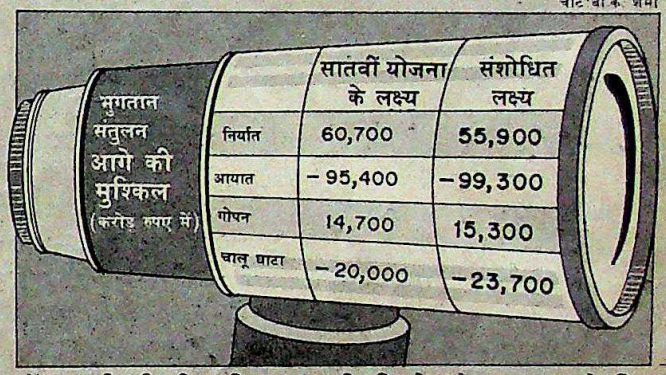

में 6.8 फीसदी की कमी रह जाएगी. पिछले और इस साल के लिए निर्यात की मात्रा में सात फीसदी की वृद्धि का लक्ष्य तो हासिल हो जाएगा पर योजना के पहले वर्ष में ही लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया था. आयात में वृद्धि हो रही है और इसके भुगतान को निर्यात की मामूली कमाई से नहीं भरा जा सकता. इसलिए आयोग ने कहा है कि आयात के मामले में कड़ाई बरतने से ही इस समस्या का समाधान हो सकता है.

रंग बदलता रंगीन टीवी

देश के रंगीन टीवी बाजार में अगले कुछ महीनों में भारी बदलाव होने जा रहा है. जल्दी ही 'फ्लैट स्क्वायर' स्क्रीन और 14 इंच वाले सेट बाज़ार में पहुंचने वाले हैं. पिक्चर ट्यूब निर्माण करने वाली कंपनियां सैमटेल और अपट्रॉन, सपाट स्क्रीन वाले पिक्चर ट्यूब बनाने लगेंगी. इसे अगल-बगल से देखने पर आकृतियों में बदलाव नहीं दिखेगा (वैसे दीवार पर टांगे जा सकने वाले पतले स्क्रीन अभी बहुत दूर की बात है). इस साल की अंतिम तिमाही तक 14 इंच वाले रंगीन सेट भी आ जाएंगे. 1987 में देश में 11 लाख रंगीन टीवी सेट बेचें गए जिनमें से 70 फीसदी की कीमत 9000 रुपए से अधिक थी. ये छोटे सेट पांच से छह हज़ार रुपए के बीच के होंगे और हो सकता है कि ये बड़े श्वेत-श्याम टीवी के बाजार को खत्म कर दें. उद्योग के बारे में भविष्यवाणी है कि 1992 में 30 लाख रंगीन टीवी सेट बिकने की उम्मीद बढ़ रही है. इनमें एक-तिहाई 14 इंच वाले सेट भी होंगे.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

राष्ट्रीय कर्जे

फंदे में फंसी अर्थव्यवस्था

अब सूद चुकाने के लिए भी सरकार की उधार लेने की क्षमता जवाब देने लगी

विकास की यह दौड़ काफी तेज लग रही थी. भाग्य का सहारा लेते हुए अपना तय लक्ष्य पाने के लिए भारतीय लोग दनादन फैक्टरियां लगाते जा रहे थे और साथ ही हजारों की संख्या में रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे थे. साल-दर-साल आय बढ़ने के साथ उनका जीवन स्तर भी बढ़ता गया. अच्छे खाते-पीते घरों में टीवी, फ्रिज, प्रेशर कुकर वगैरह पहुंच गए. गरीब लोगों की हालत भी सुधरी.

क्या समृद्धि का यह महल मजबूत नींव पर टिका था? जवाब होगा: नहीं. यह सब कुछ सरकार के वित्तीय समर्थन पर टिका था जो भारी-भरकम विदेशी कर्ज लेकर यह सब कर रही थी. और एकाएक यह कर्ज हर भारतीय के सामने उपस्थित होने वाले संकट का एक बहुत बड़ा कारण बन गया है.

और 'ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्' का यह दौर अब खत्म हो गया है और इस घी का बिल हमारे सामने हाजिर है. यह राशि 'मात्र' 10,5267 करोड़ रुपए (चार्ट देखें) है और इसका 22 फीसदी विदेशी कर्ज है.

यह तो सरकारी अनुमान है जो वास्तविकता से काफी कम है. इन आंकड़ों के अनुसार 1985 में यह कर्ज 18,153 करोड़ रुपए था जबकि विश्व बैंक का कहना है कि कर्ज 35,000 करोड़ रुपए से भी अधिक था.

पर सरकारी अनुमान भी दिमाग को चकरा देने के लिए पर्याप्त है. इसी के अनुसार देश पर कुल कर्ज पिछले साल के उसके राजस्व से तीन गुना अधिक है. असल में यह भारत के सकल घरेलू उत्पादन के करीब 66 फीसदी तक पहुंच चुका है.

आप कर्ज संबंधी सरकारी अनुमान को मानें या विश्व बैंक के अनुमान को (यह फर्क कर्ज की परिभाषा में अंतर के कारण है), पर आज हर भारतीय औरत, मर्द और बच्चे पर 1300 से लेकर 1800 रुपए के बीच कर्ज है जो अधिकांश लोगों की वार्षिक आय से अधिक है. इस हिसाब को दूसरे तरह से समझें. इतनी राशि को खर्च करने के लिए किसी खरीदार को प्रति मिनट एक लाख रुपए से भी अधिक रुपए खर्च करने होंगे और वह भी 20 साल तक दिन-रात.

हां, तीसरी दुनिया के देशों की जो हालत है उस हिसाब से अभी भी भारत थोड़ी बेहतर स्थिति में है. ब्राजील और मैक्सिको जैसे लैटिन अमेरिकी देशों ने तो इतना अधिक कर्ज ले रखा है कि अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग व्यवस्था के चरमराकर गिर पड़ने का खतरा पैदा हो गया है. 1980 के दशक के शुरू में विदेशी मुद्रा की कमाई का नौ फीसदी ही इस कर्ज के सूद को चुकाने पर खर्च होता था. आज यह मात्रा 27 फीसदी तक पहुंच गई है (सुरक्षित सीमा 20 फीसदी ही मानी जाती है). इससे पता चलता है कि भारत की हालत तेजी से बिगड़ती जा रही है.

विश्व बैंक ने (तीसरी दुनिया के) कर्ज लेने वाले 96 देशों की जो सूची बनाई है उसमें 1985 में भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कर्ज लेने वाला देश है. ब्राजील 7389.4 करोड़ डॉलर के साथ पहले, मैक्सिको 7251 करोड़ डॉलर के साथ दूसरे, कोरिया गणराज्य 2912.6 करोड़ डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर हैं. भारत पर 2974.3 करोड़ डॉलर का कर्ज था और उसके बाद इंडोनेशिया और मिस्र का नंबर था.

हाल तक बहुत कम ही लोगों को देसी या विदेशी कर्ज की चिंता थी. पर खतरे की घंटी बजते ही यह विषय एकाएक अर्थशास्त्रियों के बीच विवाद का प्रमुख मुद्दा बन गया है. इनमें से अनेक का मानना है कि यह एक नए राष्ट्रीय संकट की भी घंटी है.

बैंकों, जीवन बीमा निगम जैसे वित्तीय संगठनों और आम जनता के पैसे वाला अंदरूनी कर्ज तो इस साल सीमा को लांघ गया. यह इस स्थिति में पहुंच चुका है कि इसका सूद चुकाने में सरकार की उधार लेने की क्षमताएं भी कम पड़ने लगी हैं. कुछ अर्थशास्त्री इसे 'कर्ज का फंदा' कहेंगे जिसमें भारत लगभग फंस चुका है.

आंकड़े ही बेहतर तरीके से सारा किस्सा सुनाते हैं. 1974-75 में इस अंद-

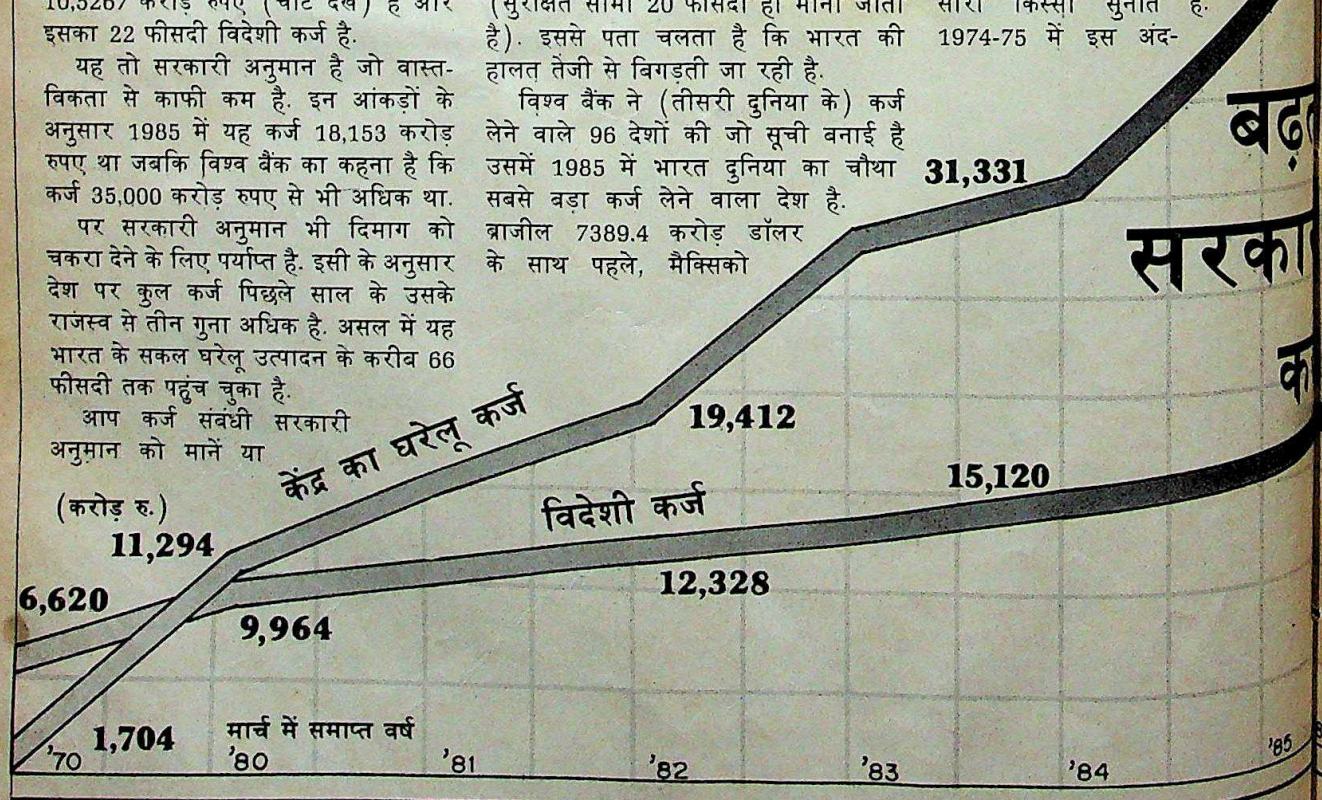

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सभी कार्टून: अजीत नाइनन

दहशत पैदा करने वाला निष्कर्ष यह है कि भारत कर्ज के फंदे में फंसने ही वाला है

रूनी कर्ज पर सरकार को 1168 करोड़ रुपए सालाना सूद चुकाना पड़ता था. इस साल इस मद में 12,270 करोड़ रुपए खर्च हुए. और 1978-79 से 1985-86 के बीच इसमें सालाना 52.1 फीसदी की चक्रवृद्धि बढ़ोतरी हुई है.

अर्थशास्त्री इन आंकड़ों के इस जोड़-घटाव पर हैरान होते हैं, पर अभी भी यह चीज एक राष्ट्रीय चिंता का विषय नहीं बनी है. जैसा कि दो वर्ष पहले अमेरिका में हुआ था. पर व्यापारी और नागरिक सावधान होने लगे हैं. सरकार स्वयं ही इतना पैसा उधार लेने लगी है कि निजी कंपनियां पूंजी बाजार के बाहर फेंकी जाने लगी हैं. सरकारी कंपनियां सूद की जिस दर पर पैसा ले रही हैं, उसे चुका पाना निजी कंपनियों के लिए संभव नहीं है. फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कामर्स ऐंड इंडस्ट्रीज (फिक्की) के महासचिव डी.एच. पाई पेनांदिकर कहते हैं, "सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के बांड असल में 20 फीसदी सूद दे देते हैं क्योंकि उन पर कर नहीं लगता. इसलिए निजी क्षेत्र की कंपनियां डिबेंचर पर 15 फीसदी सूद की सीमा होने के कारण पैसा नहीं उठा सकतीं."

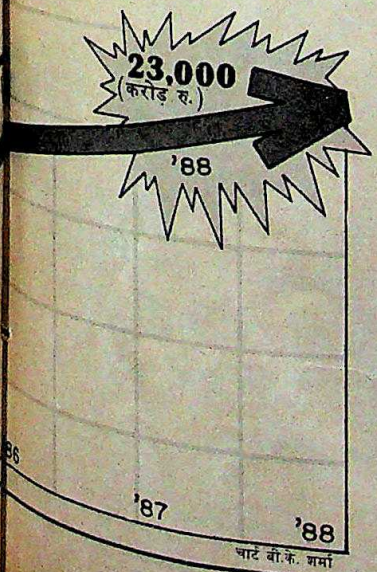

चार्ट: बी.के. शर्मा

यह तो शुरुआत भर है. जब सरकार को बैंकों से पैसा नहीं मिलता तो वह सीधे रिजर्व बैंक से कर्ज मांगती है जो नए नोट छापकर सरकार को थमा देता है. लेकिन इससे मुद्रास्फीति बढ़ती है. दिल्ली के आर्थिक विकास संस्थान के प्रोफेसर बी.बी. भट्टाचार्य चेतावनी देते हैं, "अगर सरकार अभी स्थिति को संभालने पर ध्यान नहीं देती तो हम लैटिन अमेरिकी देशों जैसी हालत में पहुंच जाएंगे."

और यह बढ़ता जा रहा कर्ज अगली पीढ़ियों पर भी बोझ बनेगा. रिजर्व बैंक के हाल के एक अध्ययन में अमेरिका के दिवंगत राष्ट्रपति हरबर्ट सी. हूवर को यह कहते हुए उद्धृत किया गया है, "शापग्रस्त तो वह नई पीढ़ी है जिसे राष्ट्रीय कर्ज का बोझ विरासत में मिलेगा." अगर हालत बिगड़ी तो अगली पीढ़ी के लिए और भी मुश्किलें आएंगी. अन्य जगहों का अनुभव भी यही बताता है. भट्टाचार्य बताते हैं कि कर्ज में डूबे अफ्रीकी देशों में आज वास्तविक आय एक दशक पहले से भी कम हो चुकी है. अगर ऐसा होता है तो 40 साल में हासिल विकास पर पानी फिर जाएगा.

हो सकता है कि कर्ज का यही पाप सरकार को महंगा पड़े. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के प्रोफेसर प्रभात पटनायक बताते हैं कि राजनैतिक हंगामे की जड़ में अक्सर आर्थिक कारण ही होते हैं. वे बताते हैं, "फ्रांस की क्रांति भी आर्थिक कारणों से हुई थी. जब महंगाई बढ़ती है तो अक्सर सरकार बदल दी जाती है."

कुछ सरकारी अर्थशास्त्रियों का मानना है कि कर्ज का हंगामा बेकार मचाया जा रहा है. लेकिन सरकार के बाहर के प्रमुख अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अगर संकट आ नहीं गया है तो बस आने ही वाला है. एक प्रमुख सहायता एजेंसी के अर्थशास्त्री कहते हैं, "अभी से दबाव पड़ना शुरू हो गया है लेकिन सरकार उसे देख नहीं पा रही है."

कर्ज लेने के सरकार के कई तरीके हैं:

- बैंक की वैधानिक भुगतान अनुपात को बढ़ाकर वह खुद के लिए अधिक और निजी क्षेत्र के लोगों के लिए कम पैसा देने की व्यवस्था कर लेती है.
- घाटे की अर्थव्यवस्था का सहारा लेना: जिसमें रिजर्व बैंक से आगे भुगतान करने के वायदे पर कर्ज जाते हैं और यह भुगतान कभी किया नहीं जाता. नया कर्ज लिया जाता है और बैंक नए नोट छापकर देता है.
- बांड जारी करके वह लोगों और वित्तीय संस्थाओं से पैसा जुटाती है.

शापग्रस्त तो वह नई पीढ़ी है जिसे राष्ट्रीय कर्ज का बोझ विरासत में मिलता है

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

केंद्र के अतिरिक्त राजस्व का 74 फीसदी रक्षा, खाद्य और उर्वरक की सबसिडी पर खर्च होगा

केंद्र ये तीनों ही तरीके अपनाता रहा है, पर इसमें सबसे अधिक प्रचार बजट के घाटे और बाजार से सीधे पैसा उठाने को मिलता है. योजनाकृत खर्चों के लिए पूंजी जुटाने के लिए इसके तरकस में तरह-तरह के तीर भरे पड़े हैं. टैक्स बढ़ाकर या उसका दायरा बढ़ाकर, विदेशों से कर्ज लेकर और देश में ही कर्ज लेकर भी ये काम कर सकते हैं. कर या उसका दायरा बढ़ाना राजनेताओं के लिए मुश्किलें पैदा करता है और विदेश कर्ज लेने से राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सवाल उठने लगता है. इसलिए केंद्र ने तीसरा रास्ता चुना और उसका नतीजा आज सामने है.

यहां दो बातें हुईं. पिछले दो दशकों में सरकारी बांडों पर दिए जाने वाले सूद की दर करीब 4.5 फीसदी से बढ़कर 11.5 फीसदी के आसपास पहुंच गई. और इस सूद को साधना ही केंद्र के लिए महंगा पड़ने लगा. एक सीमा तक उसने राज्यों को दिए जाने वाले कर्ज पर सूद की दर बढ़ाकर इस बोझ को कुछ हल्का किया. लेकिन इससे राज्यों पर बोझ बढ़ गया. पश्चिम बंगाल के वित्तमंत्री असीम दासगुप्त शिकायत करते हैं कि सूद की दर बढ़ते जाने के साथ ही राज्यों पर केंद्र की देनदारियां बढ़ती जा रही हैं. वे कहते हैं, "हमें जितना पैसा मिलता है, उससे अधिक तो हमें भुगतान ही करना पड़ रहा है. केंद्र की कृपा से हम कर्ज के फंदे में फंस गए हैं." अन्य राज्यों के सामने भी यही मुश्किल है.

दूसरे, केंद्र ने दीर्घकालिक ऋण लेना शुरू कर दिया. इससे तुरंत भुगतान का झमेला तो खत्म हुआ, पर सूद की दर अधिक देनी पड़ी.

और इन दो चीजों का बहुत ही भयंकर असर हुआ. सूद चुकाने में ही 1986-87 में लिए गए अंदरूनी कर्ज का दो-तिहाई हिस्सा निकल गया. योजना आयोग के सदस्य राजा चेल्लियाह का यह कहना सही है कि सूद चुकाने में केंद्र और राज्यों के कुल राजस्व का 13 फीसदी ही खर्च होता है. लेकिन वे भी मानते हैं कि केंद्र के कर्ज लेने की भी एक सीमा होती है.

इस बात के संकेत मिलने लगे हैं कि कर्ज का फंदा लग चुका है. पिछले साल सरकार ने घरेलू बाजार से 5300 करोड़ रुपए की पूंजी उठाई. इस साल इसके 6300 करोड़ रुपए तक जाने की उम्मीद है. सीधा बात करने के लिए विख्यात अर्थशास्त्री मिन्हास कहते हैं, "सरकार जितनी अतिरिक्त पूंजी उठाएगी, उससे अधिक राशि उसे अतिरिक्त सूद के रूप में चुकानी पड़ेगी. इसका क्या मतलब हुआ?" दहशत पैदा करने वाला निष्कर्ष यही है: भारत इस जाल में फंसने जा रहा है. योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डी.टी. लाकड़ावाला चेतावनी देते हैं, "हम कर्ज के फंदे में फंस चुके हैं. अब संकट और गहरा होगा."

स्पष्ट है कि कर्ज वाली बहस का बुनियादी मुद्दा है यह पैसा कहां लग रहा है. और इसी मुद्दे पर केंद्र चारों खाने चित हो जाता है. नेशनल कौंसिल ऑफ एप्लाइड इकानॉमिक रिसर्च (एनसीएइआर) के महानिदेशक आई.जेड. भट्टी कहते हैं, "अगर आप खर्च से अधिक कमाई कर लेते हैं और आपका निवेश बचत करा देता है तो कर्ज लेने में हर्ज नहीं है. पर यहां यह बात लागू नहीं होती और यही मुश्किल है. मुझे नहीं लगता कि हम कगार पर खड़े हैं. वैसे अगर ध्यान नहीं दिया गया तो गिरने की नौबत भी आ सकती है."

योजना आयोग ने सातवीं योजना की जो मध्यावधि समीक्षा की है, उससे पता चलता है कि इस साल केंद्र के राजस्व का 74 फीसदी हिस्सा (चार्ट देखें) प्रतिरक्षा, सूद अदायगी, खाद्य और खाद पर दी जाने वाली सबसिडी में जाएगा. इसमें से किसी को भी उत्पादक खर्च नहीं माना जा सकता. आयोग ने एक और बहुत ही जबरदस्त टिप्पणी की है—इस सबका दोषी केंद्र है, राज्य सरकारें नहीं.

सरकार ने अपना अधिकांश पैसा प्रशासन, अधिकारियों और सेना के वेतन पर खर्च किया है और यह पैसा देश के असल बचत करने वालों की जेब का है. फिक्की के पाई पेनांदिकर कहते हैं, "असल में हम लोगों की गाढ़ी कमाई के पैसे को बर्बाद करते रहे हैं. सरकार अगर इसे बेकार के मामलों पर खर्च करती है तो उसे कर्ज लेने का कोई अधिकार नहीं है."

प्रतिरक्षा और सबसिडी (कुछ पैसा गरीबों को सस्ता अनाज देने पर खर्च होता है) का खर्च पूरी तरह बेकार नहीं है. लाकड़ावाला बताते हैं, "हमने सड़क वगैरह पर खर्च किया है जो आर्थिक रूप से तो नहीं पर सामाजिक रूप से उत्पादक है." पर सार्वजनिक क्षेत्र में, जो उत्पाद आर्थिक रूप से भी काफी उत्पादक हो सकता था, पूंजी लगाने का हिसाब जोड़ने पर यह बोझ बरदाश्त के बाहर हो गया लगता है. सरकार अपने पूंजी निवेश पर कर के बाद की जो कमाई कर पाती है वह औसत 2.8 फीसदी है जबकि बाजार से 14 फीसदी सूद पर पैसा लिया जाता है.

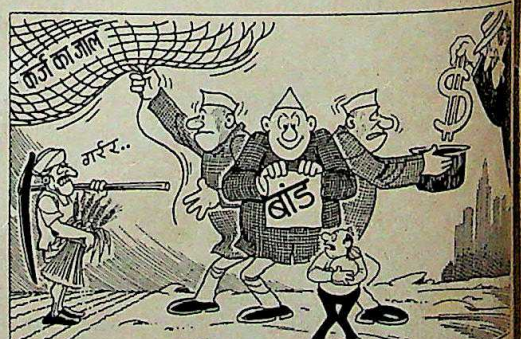

पैसा जुटाने के तीन विकल्प: कर का दायरा बढ़ाने का अलोकप्रिय कदम; देश की प्रभुसत्ता को प्रभावित करते विदेशी कर्ज; देश में ही कर्ज जुटाना

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारी पैमाने पर कर्ज लेने में कोई हर्ज भी नहीं है बशर्ते कि वह पैसा सही जगह पर ही लगे

किस चीज पर से सबसिडी वापस ली जाए यह चुनाव करना काफी मुश्किल काम है पूर्व वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी पिछले साल वनवासी क्षेत्रों को दिए गए 20 लाख टन अनाज का उदाहरण देते हैं, "प्रति किलो 50 पैसे की सबसिडी दी जाती है और इसका मतलब हुआ इतने अनाज पर 200 करोड़ की सबसिडी. भला किस तरह से गैर-विकास खर्च को कम किया जाए? खर्चों के लिए सरकार को और कर्ज लेना ही होगा." केंद्र पूर्वोत्तर के और अन्य अविकसित राज्यों का पूरा विकास खर्च वहन करता है. और पिछले कुछ वर्षों से इन मामलों में जब भी सरकार के लिए कड़े फैसले का वक्त आया उसने किसी तरह इधर-उधर करके जान बचाई. लेकिन इससे समस्या गहराती गई. पहले सरकारी राजस्व इतना होता था कि सामान्य खर्चों के बाद भी निवेश के लिए पैसा बचा रहता था. आज सरकार का सामान्य खर्च ही कर राजस्व से अधिक हो गया है. इसलिए सरकार अब प्रशासन चलाने के लिए ही कर्ज लिए जी जा रही है.

पर इससे भी बुरी हालत अभी आनी है. योजना आयोग की भविष्यवाणी है कि अगर आय-व्यय इसी तरह चला तो 1994-95 तक राजस्व और खर्च के बीच का फासला बढ़कर 50,000 करोड़ रुपए हो जाएगा.

अगर खर्च की रफ्तार बढ़ती गई तो कर्ज लेने का एक और पक्ष बहुत विकराल रूप धारण कर लेगा. धीरे-धीरे बजट का घाटा नियंत्रण के बाहर होता चला गया है. छठी योजना के दौरान 10,785 करोड़ रुपए की सीमा छू लेने के बाद सातवीं योजना में इसके 30,000 करोड़ रुपए के ऊपर पहुंच जाने का अंदेशा है और तब मुद्रास्फीति की दर आसमान पर ही पहुंच जाएगी. बजट का घाटा अर्थव्यवस्था में और मुद्रा का प्रवेश करा देता है. और अनेक अर्थशास्त्री मानते हैं कि भविष्य में भारत में और इससे भी कहीं अधिक महंगाई आने वाली है.

आगे कर्ज लेते हुए संयम बरता जाए इसके अलावा कर्ज के फंदे से बचने के बहुत ही कम रास्ते बचे हैं. चेल्लियाह कहते हैं कि एक रास्ता तो यह है कि सरकार आय और व्यय में संतुलन कायम करे. इसमें विकास की दर कम हो जाने का खतरा उठाते हुए नई परियोजनाओं को भी बंद किया जा सकता है. वे कहते हैं, "हालात सुधारने के लिए कुछ कदम तो उठाने ही पड़ेंगे."

दूसरा रास्ता कर के जाल को और बड़ा करना है. कर राजस्व वैसे तो बढ़ गया लगता है पर सकल घरेलू उत्पादन के अनुपात में वह 16.4 फीसदी के आसपास अटका है. यह दर 1979-80 की है जबकि 1974-75 में यह 13 फीसदी ही थी. जहां सकल घरेलू उत्पादन और कर का अनुपात एक ही जगह रुका पड़ा है, वहीं सकल घरेलू उत्पादन और कर्ज का अनुपात तेजी से बढ़ता जा रहा है. पर अधिकांश लोग मानने लगे हैं कि यह एक सीमा तक ही बढ़ सकता है.

नया कर दो क्षेत्रों—असंगठित उद्योग और कृषि आय पर लग सकता है. एनसीएइआर के भट्टी कहते हैं कि यह मानना गलत है कि असंगठित क्षेत्र से कर वसूला ही नहीं जा सकता. "अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की तुलना में असंगठित क्षेत्र की वृद्धि दर अधिक है. इस क्षेत्र की जितनी आय पर कर लगता है, उसकी दो गुनी राशि तो कर दिए बिना ही छूट जाती है."

अन्य अर्थशास्त्रियों का भी मानना है कि कृषि आय पर कर लगाने से काफी पैसा आ सकता है. लेकिन सूखे वाले वर्ष में यह फैसला बहुत अलोकप्रिय हो जाएगा. सरकार 1989 के आम चुनावों पर नजर गड़ाए हुए है इसलिए भी इसकी संभावना नहीं लगती. लेकिन सरकार के सामने और रास्ते नहीं हैं. प्रणव मुखर्जी कहते हैं, "क्या चीज अधिक अलोकप्रिय होगी? सरकार की ही छुट्टी हो जाना या कृषि की आय पर कर लगाना?"

तीसरे इलाज पर भी हंगामा मचेगा. सिंचाई और शिक्षा पर दी जाने वाली सबसिडी की मात्रा भी कम करनी होगी.

भारतीय लोगों ने मुफ्त सवारी का काफी मजा ले लिया है. अब यह दौर खत्म होता लग रहा है. अब लोग पसंद करें या नहीं, सवारी का भाड़ा तो उन्हें चुकाना ही पड़ेगा. इसलिए लोग भले ही नाक-भौं सिकोड़ें, टैक्सों का नया दौर बस अब जल्दी ही आने वाला है.

—पलकुन्नयु जी. मथाई
ब्यूरो रिपोर्टों के साथ

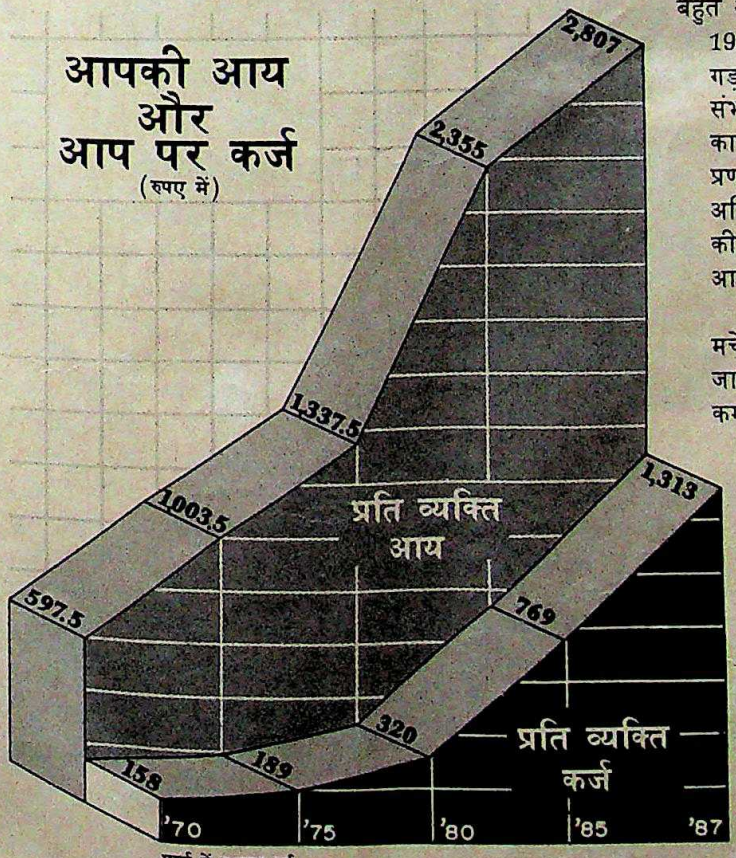

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

डीसीएम

आखिरी मौका

श्रीराम घराना बंटने के कगार पर

हाथ से लिखी चिट्ठी का मजमून था, "मेरे प्रिय चरत, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मूल्यों और जीवन तथा काम के प्रति हमारे अलग-अलग दृष्टिकोण के कारण अब हमारे लिए एकमात्र रास्ता यही बचा है कि अपनी व्यापारिक गतिविधियों का बंटवारा कर लें. मुझे पक्का भरोसा हो गया है कि अब मैं और तुम डीसीएम में एक साथ नहीं रह सकते. मैं बोर्ड की अगली बैठक में इस मुद्दे को भी रखना चाहूंगा..."

30 दिसंबर 1983 को यह चिट्ठी लिखी थी 500 करोड़ रुपए कारोबार वाली डीसीएम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक भरत राम ने. चिट्ठी छोटे भाई और कंपनी के प्रबंध निदेशक चरत राम के नाम थी.

विवाद में उलझी इस कंपनी के बंटवारे की योजना जल्दी ही स्थगित कर दी गई और बड़ी शांति से श्रीराम परिवार की अगली पीढ़ी ने कंपनी की जिम्मेदारियां बांट लीं. लेकिन चार महीने पहले यह बात फिर उठी. कंपनी के मौजूदा अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बंसीधर ने कहा कि अगर प्रबंध संभालने वाले लोग आपसी सहमति के अभाव में इसका कामकाज नहीं सुधार सकते तो बेहतर होगा कि कंपनी को तीन हिस्सों में बांटकर तीन चचेरे भाइयों (बंसीधर, विनय भरत राम और सिद्धार्थ श्रीराम) को छोटी कंपनियों की जिम्मेदारी सौंपी जाए.

हो सकता है कि बंटवारा अब भी टल जाए. लेकिन निश्चित रूप से डीसीएम भारी मुश्किल में है. कंपनी के बड़े लोग भी यह कबूल करते हैं. पिछले दो साल से एकाउंटिंग के दांवपेचों के चलते कंपनी के घाटे की अधिकृत घोषणा भी नहीं की गई है. इस (जून में समाप्त होने वाले) वित्त वर्ष में भी तय है कि घाटा होगा. और निश्चित माना जा रहा है कि लगातार दूसरे साल निवेशकों को लाभांश नही मिल पाएगा. अनेक धंधों में लगी देश की इस प्रमुख कंपनी के लिए अब जैसे 'करो या मरो' की स्थिति आ गई है.

नई योजना के अनुसार प्रबंध में श्रीराम परिवार के लोगों की भूमिका घटनी ही है यानी कंपनी के चीनी और वित्त विभाग देखने के लिए बाहर के प्रबंधक बुलाना और नई प्रबंध समिति का जिम्मा परिवार के बाहर के एक तीसरे सदस्य को सौंपना. इस समिति को हर हफ्ते बैठकर कंपनी का कामकाज सुधारने के कदमों की समीक्षा करने का काम सौंपा गया है. परिवार के लोगों में से सिद्धार्थ श्रीराम को कंपनी के मुश्किल में फंसे कपड़ा विभाग को संभालने का जिम्मा सौंपा गया है. इस इकाई को पिछले दशक में 130 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा है. स्पष्ट है कि अब सिद्धार्थ को परिवार का नया संकटमोचन माना जा रहा है.

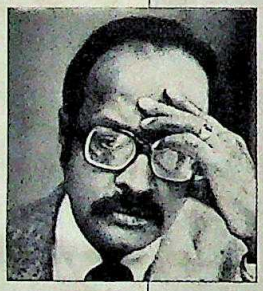

(ऊपर से) बंसीधर, विनय भरत राम और सिद्धार्थ

चार महीने पहले डीसीएम के अध्यक्ष बंसीधर ने सुझाव दिया था कि कंपनी को तीन हिस्सों में बांटकर तीनों चचेरे भाइयों बंसीधर, विनय भरत राम और सिद्धार्थ श्रीराम को छोटी कंपनियों की जिम्मेदारी सौंपी जाए

तीन साल पहले ऊपरी प्रबंध में तब्दीली से खुली लड़ाई पर तो विराम लग गया पर इससे उच्च प्रबंध में वैसा एका नहीं हो पाया जैसा होना चाहिए था. फिर साल भर पहले दो प्रबंध निदेशकों वाली व्यवस्था समाप्त करने और बंसीधर को प्रमुख मान लेने पर विनय और सिद्धार्थ सहमत हो गए. प्रबंधकीय सलाहकार की रिपोर्ट के आधार पर काम का फिर बंटवारा हुआ. नए लक्ष्य तय किए गए तथा नई योजनाएं बनाई गईं.

लेकिन वांछित बदलाव नहीं हुआ और कंपनी की हालत खराब होती गई. कंपनी की वार्षिक आम बैठक (दिसंबर) में शेयर होल्डरों ने बुरा-भला कहना शुरू कर दिया और कंपनी के कर्ताधर्ता लोगों को भी लगा कि अब कुछ करना जरूरी है.

दरअसल बदलाव की योजना सितंबर में ही बन गई थी. यह योजना श्रीराम फाइबर्स और डीसीएम टोयोटा जैसी कंपनियां चलाने वाले परिवार के नौजवान लोगों ने बनाई.

परिवार के कुछ वरिष्ठ लोगों के गले यह बात उतारने में मुश्किल पेश आई क्योंकि उन्हें पद छोड़ना यानी अपनी सत्ता का समाप्त होना लग रहा था. लेकिन वित्तीय संस्थाओं ने भी नई योजना पर अमल करने के लिए दबाव डाला और ऐसा ही हुआ. इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड के अवकाश-प्राप्त अध्यक्ष एस.एस. वैजल को नए प्रबंधक मंडल का प्रमुख बनाया गया.

सबसे पहले सामान्य कामकाज चलाने लायक पूंजी के अभाव में बंद होने वाले विभागों के लिए पैसा जुटाने का लक्ष्य तय किया गया. कंपनी का जो नया मुख्यालय तैयार हो रहा है उसे बेचकर 10 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे. बैंकों से मिलने वाला व्यापारिक कर्ज जल्दी ही उठा लिया जाएगा.

कंपनी के कामकाज में आई सुस्ती दूर की जा रही है. कपड़ा विभाग के 60 अधिकारियों को भ्रष्टाचार और अक्षमता के आरोप में हटाया जा चुका है तथा 100 दूसरे भी हटाए जाएंगे. खाद और सीमेंट तथा डाटा प्रोडक्ट विभाग के कारोबार को भी चुस्त-दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है. अगर कंपनी की दिल्ली स्थित कपड़ा मिल बंद करने और उस जमीन को बेचने की योजना पूरी हो जाती है तो इस मुश्किल घड़ी में कंपनी को करीब 250 करोड़ रुपए तक मिल सकते हैं. यह मामला अदालत में है. अगर कानूनी झमेले खत्म हो जाते हैं और मुश्किल में पड़े विभागों को बंद कर दिया जाता है तो डीसीएम की स्थिति सुधर सकती है. श्रीराम परिवार के एक सदस्य कहते हैं, "हमने जिस तरह से अनेक समाधान तलाशने की कोशिश की है, उससे साबित होता है कि हम कंपनी के हक में अपना नियंत्रण छोड़ रहे हैं."

और इस बात में संदेह नहीं कि अब आखिरी मौका ही रह गया है. उसके बाद तो देश की इस नामी कंपनी को बंटना ही पड़ेगा.

—टी.एन. नाइनन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जब लौटे हों शॉपिंग करके और थके हों दिन भर के...

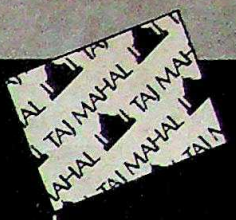

तो डिप लीजिये!

जब आपको झटपट एक कप मनपसन्द चाय की ज़रूरत पड़े, तब ताज महल टी बैग की सुविधा को अपनाइये. न कोई झंझट, न झमेला.

एक कप में एक ताज महल टी बैग रखिये. ताज़ा उबलता पानी डालिये. दो या तीन मिनट तक रखे रहिये. फिर टी बैग निकाल लीजिये. अपने स्वाद के अनुसार दूध और शक्कर मिलाइये. बस हो गई आपकी चाय तैयार!

कप हो या चायदानी. दोनों में आसानी. (यदि आप चायदानी में चाय बना रहे हैं, तो 4 कप के लिये 3 टी बैग काफी हैं)

ताज महल टी बैग

स्वाद व शान. बनाना आसान!

ब्रुक बॉंड पैकेट चाय.
हर पैकेट में एक-सी, भरोसेमंद क्वालिटी.

haridwar

HTA 8619

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मध्य प्रदेश

चमक धुंधलाई

हीरा खुदाई अब संकट में पड़ी

हीरे की खानों के लिए विख्यात मध्य प्रदेश के उत्तर-पूर्वी जिले पन्ना को अब अपनी शोहरत कायम रखने के दूसरे तरीके ढूंढने होंगे. देश में हीरा उत्पादन के इस केंद्र में अब यह धंधा दिनोदिन मंदा होता जो रहा है. आशंका है कि कहीं यह बिलकुल ही खत्म न हो जाए.

लगभग दो शताब्दियों से हजारों की तादाद में लोग इसी उम्मीद में यहां आते रहे हैं कि इस बेशकीमती पत्थर की चमक शायद उनका भाग्य बदल देगी. लेकिन पिछले दो वर्षों से यह संख्या लगातार कम होती जा रही है. 1960 से इस काम में लगे सार्वजनिक क्षेत्र के 'राष्ट्रीय खनिज विकास निगम' (एनएमडीसी) की मशीनीकृत खानें 1960 से घाटा उठाती आ रही हैं, नतीजतन निगम का कामकाज जारी रखा जाए या नहीं इसी पर सवाल उठने लगे हैं.

पन्ना की मुसीबतों की शुरुआत 1980 में केंद्रीय वन संरक्षण कानून लागू होने के साथ ही हो गई थी. इस कानून में दीगर पाबंदियों के अलावा वन क्षेत्रों में खुदाई की भी मनाही की गई है. तब सरकार ने 100 वर्ग किलोमीटर में फैले इस क्षेत्र में 625 वर्ग फुट के 11,000 पट्टे लोगों को दिए हुए थे. सरकार इनसे हर साल पांच रुपए नाममात्र का पट्टा-शुल्क वसूल किया करती थी.

तब इन निजी छिछली खदानों से औसतन 1,000 कैरेट हीरे (एक कैरेट—लगभग 200 मिलिग्राम) हर साल निकल आते थे. इन हीरों को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाता था. सरकार साल में दो बार इनकी नीलामी करती थी और उस आय का 20 प्रतिशत रायल्टी के तौर पर अपने पास रखकर बाकी रकम हीरे खुदाई करने वालों को दे देती थी.

कुछ सालों तक तो राज्य सरकार वन संरक्षण कानून लागू करने में ढील दिखाती रही. दो साल पहले ही खनन विभाग ने वन क्षेत्र में खनन पट्टों का नवीकरण बंद किया. इस समय 2,500 खदानें पट्टों पर चल रही हैं. इसी कारण हीरों का वार्षिक उत्पादन 1986 में 200 कैरेट रह गया.

1980 के कुल हीरा उत्पादन में निजी खुदाई करने वालों का योगदान वैसे भी बहुत कम रहा था. ज्यादातर हीरे पन्ना से 25 किमी दूर एनएमडीसी की मशीनीकृत खदान से ही निकले थे. एनएमडीसी छह वर्ग किलोमीटर में फैले क्षेत्र में लगभग चालीस फुट गहरी खुली खदानों में खनन करवाती है. लगभग 750 कामगार इसमें जुटे हुए हैं. पिछले साल निगम ने 15,000 कैरेट हीरों का उत्पादन किया था.

15,000 कैरेट सुनने में भले ही उत्साहवर्धक लगे लेकिन एनएमडीसी का धंधा बिलकुल भी अच्छा नहीं चल रहा है. मझगांव खान के एक प्रवक्ता के अनुसार, "मजदूर जरूरत से ज्यादा हैं और लागत हर साल बढ़ती जा रही है." पिछले साल निगम ने प्रत्येक कैरेट की खुदाई पर 3,200 रुपए खर्च किए, जबकि बिना पालिश किए एक कैरेट से होने वाली आय केवल 1,600 रुपए ही रही. इसी कारण घाटा बढ़ता जा रहा है. पिछले साल यह 2.50 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा.

वन संरक्षण कानून लागू किए जाने से निजी खुदाई वालों के साथ-साथ एनएमडीसी की मशीनीकृत खदानों का काम भी ठप पड़ गया है

समझा जाता है कि वन संरक्षक कानून के कारण खनन क्षेत्र बढ़ाने में असमर्थता और दिनोदिन बढ़ते घाटे के कारण एनएमडीसी ने हाल में अपनी मशीनीकृत खानें बंद करने का प्रस्ताव रखा है. केंद्र सरकार ने इस पर अभी कोई फैसला नहीं किया है.

मुश्किल यह है कि वन क्षेत्र से बाहर की सभी खानों में खुदाई लगभग की जा चुकी है. फिर यही रास्ता बचता है कि नए क्षेत्रों में खुदाई शुरू की जाए. पन्ना और पड़ोसी जिले सतना के लगभग 1,200 वर्ग किमी क्षेत्र में ही हीरा मिलता है और 15 फीसदी इलाके में ही खुदाई अब तक हुई है.

1981 में केंद्र ने हीरे की खुदाई में तेजी लाने के लिए 3.5 करोड़ रुपए लागत का एक तीन वर्षीय कार्यक्रम बनाया जिसका उद्देश्य नए हीरे मिलने के नए स्थानों और हीरे के खनन की व्यावसायिक संभावनाओं का मूल्यांकन करना था. लेकिन यह महत्वाकांक्षी योजना अगले वर्ष ही धराशायी हो गई क्योंकि हीरे मिलने की संभावना वाला अधिकांश इलाका वनों में पड़ता था.

इसी कारण एनएमडीसी ने हीरे की संभावना वाले पन्ना जिले के हातुपर क्षेत्र में खुदाई का विचार भी छोड़ दिया है. पड़ोसी सतना जिले में हीरे के नए क्षेत्र तलाशने की निगम की कोशिशें दिसंबर 1982 में ही ठप हो गई क्योंकि वनाधिकारियों ने जंगल

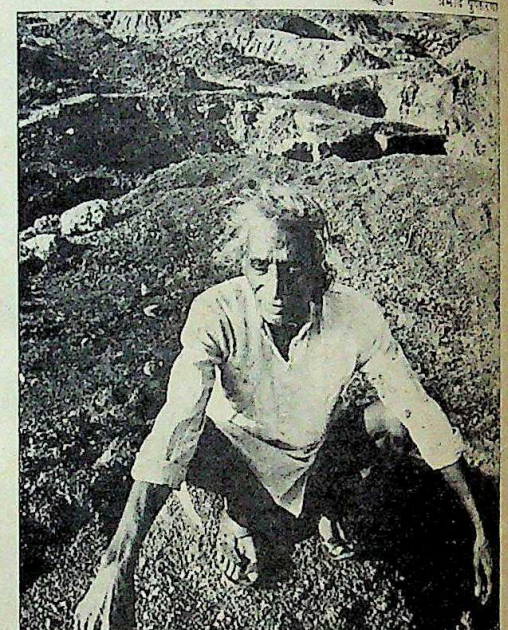

एक निजी खनिक: काम छिना

में ड्रिलिंग मशीनें लगाने पर आपत्ति की.

लेकिन खदानें बंद होने या नए इलाकों में खुदाई न कर सकने का एक नतीजा तो यह है कि खुदाई करने वाले हजारों लोगों के हाथ से काम छिन गया है. राज्य सरकार केंद्र के सामने उनका पक्ष रख चुकी है.

लेकिन इनमें रामलाल का मामला अत्यंत मर्मस्पर्शी है. पिछले साल उसके हाथ दो हीरे लगे थे और आने वाले महीनों में भी उसे किस्मत चमक उठने का पक्का भरोसा था. पर वन विभाग ने उसे मिले भूखंड में एक खाई खोद दी है. विभाग अगले साल वहां वृक्षारोपण भी करेगा. यह स्थानीय लोगों की आशाओं का अंत तो है ही भारत के हीरा उद्योग की मृत्यु का सूचक भी है.

—नरेंद्र कुमार सिंह, पन्ना से

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वार्षिक योजनाएं

स्रोतों का सूखा

राज्यों के योजना निवेश में कमी

केंद्रीय बजट के आने में दो हफ्ते से भी कम का समय है. पर बुरी खबरें आना शुरू हो गई हैं. पिछले कुछ हफ्तों से एक के बाद दूसरे राज्य ने अपनी वार्षिक योजनाओं में बहुत कम वृद्धि की है. यह संकेत है कि लोगों की अंटी में बहुत पैसा नहीं बचा है और इससे योजना निवेश की रफ्तार धीमी हो जाएगी. सातवीं योजना की मध्यावधि समीक्षा में भी संसाधनों की कमी का रोना रोया गया है और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज का सुझाव दिया गया है. ऐसे में 29 फरवरी को पेश किए जाने वाले बजट में कुछ कड़वी बातें जरूर रहेंगी.

राज्यों के 1988-89 की वार्षिक योजनाएं अगले संकट का एहसास दिलाती हैं. योजना आयोग की बातचीत के बाद तैयार 15 राज्यों की आगामी साल की योजनाओं में पूंजी निवेश में मात्र 6.4 फीसदी वृद्धि दिखाई गई है जबकि पिछले दो वर्षों में हर साल 20 फीसदी की बढ़ोतरी हो रही थी. इस साल कीमतों में 10 फीसदी से अधिक की वृद्धि के कारण असल में निवेश कम ही हो जाएगा.

अनेक राज्य जिस वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहे हैं, उसमें इस बात का अंदेशा था ही. केरल सरकार ने ओवरड्राफ्ट की सीमा पार कर दी है, सो रिजर्व बैंक अब उसके चेक भुना नहीं रहा. उत्तर प्रदेश सरकार को अपने कर्मचारियों का वेतन देने में ही मुश्किल हो रही है. ओडीसा सरकार तो निवेश के लिए संसाधन जुटाने के लिए सरकारी जमीन को ही बेचने की सोच रही है.

केंद्र की समस्याओं ने और गुड़गोबर किया है. अगले साल (घरेलू संसाधनों से) बजट समर्थन सिर्फ 12,500 करोड़ रुपए का होगा हालांकि चालू वित्त वर्ष में यह 13,000 करोड़ रुपए का है. और फिर यह हालत भी तब है जबकि केंद्र ने बहुत से राज्यों के हिस्से के कुछ पैसे पर भी कब्जा किया है. उसने सरकारी भविष्य निधि कोष (जिसका कुछ हिस्सा राज्यों को मिलता है) को डाकघर से लेकर अपने खाते में डाल लिया है जिसका पश्चिम बंगाल के वित्तमंत्री असीम दासगुप्त ने काफी विरोध किया था. अपनी योजना राशि में पांच फीसदी से भी कम की वृद्धि मिली तो राज्य के मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण ने प्रधानमंत्री से तुरंत पक्षपात की शिकायत की.

इस बीच योजना खर्चों की स्थिति सरकारी आंकड़ों में किए जाने वाले दावों से भी बदतर हो गई है. मसलन आंध्र प्रदेश ने 1988-89 के लिए 1250 करोड़ रुपए के योजना निवेश की घोषणा की. लेकिन मूल्यांकन में उसके संसाधन मुश्किल से 1000 करोड़ रुपए के माने गए. उत्तर प्रदेश की 2600 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना मंजूर तो कर ली गई पर राज्य के संसाधनों से 1900 करोड़ रुपए भी मुश्किल से जुट पाएंगे.

चालू वित्त वर्ष में भी ऐसा लगता है कि अनेक राज्य योजना निवेश के मामले में पीछे रह जाएंगे.

पी. शिवशंकरः रास्ता नजर नहीं आता

हरियाणा के मुख्यमंत्री देवीलाल ने साफ तौर पर माना कि उनके राज्य में निवेश 585 करोड़ के लक्ष्य पर न पहुंचकर मात्र 430 करोड़ रुपए का ही होगा. कर्नाटक के मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े भी खुलेआम कह चुके हैं कि इस साल 870 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले वे 720 करोड़ रुपए से अधिक निवेश नहीं कर सकेंगे.

स्पष्ट रूप से अधिकांश राज्य सरकारें ऐसी वित्तीय समस्याओं में उलझती जा रही हैं जिनका समाधान उन्हें सूझ नहीं रहा. योजना आयोग के अधिकारी मानते हैं कि इसका एक कारण तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वगैरह में कल्याण कार्यक्रमों पर बढ़ता खर्च है. आंध्र प्रदेश में दो रुपए किलो चावल उपलब्ध कराने से राज्य सरकार पर 200 करोड़ रुपए सालाना का बोझ पड़ रहा है. और इस सबसिडी को कम करने की अधिकारियों की किसी भी सलाह पर मुख्यमंत्री एन.टी. रामराव ध्यान देने को तैयार नहीं.

इस साल दूसरी मुख्य समस्या सूखे से आई और इससे अधिकांश राज्यों के राजस्व में कमी आ गई. सूखा राहत कार्यक्रम का भी बोझ ऊपर से आ गया.

राज्य के बिजली बोर्डों, परिवहन निगमों आदि का बढ़ता घाटा, सरकारी कर्मचारियों के वेतन और महंगाई भत्ते के बढ़ते बोझ जैसी दूसरी मुश्किलें भी रहीं.

संसाधनों की इतनी मुश्किल वाली स्थिति में भी योजना की कटौती की शिकायत मुख्यमंत्रियों ने नहीं की. पहले ऐसी शिकायतें आम थीं. सिर्फ एक बार त्रिपुरा के तत्कालीन मुख्यमंत्री नृपेन चक्रवर्ती ने बैठक का बहिष्कार करने की धमकी दी थी पर बाद में उन्हें भी उम्मीद से ज्यादा राशि मिल गई. समस्या यह है कि राज्यों को कुल मिलाकर इतना कुछ नहीं मिलता जिससे वे योजना निवेश के उत्साहजनक माहौल को बनाए रखें. इसी महीने के आखिर में आने वाला बजट ही बताएगा कि क्या केंद्र भी बेहतर हालत में है या नहीं.''

—टी.एन. नाइनन

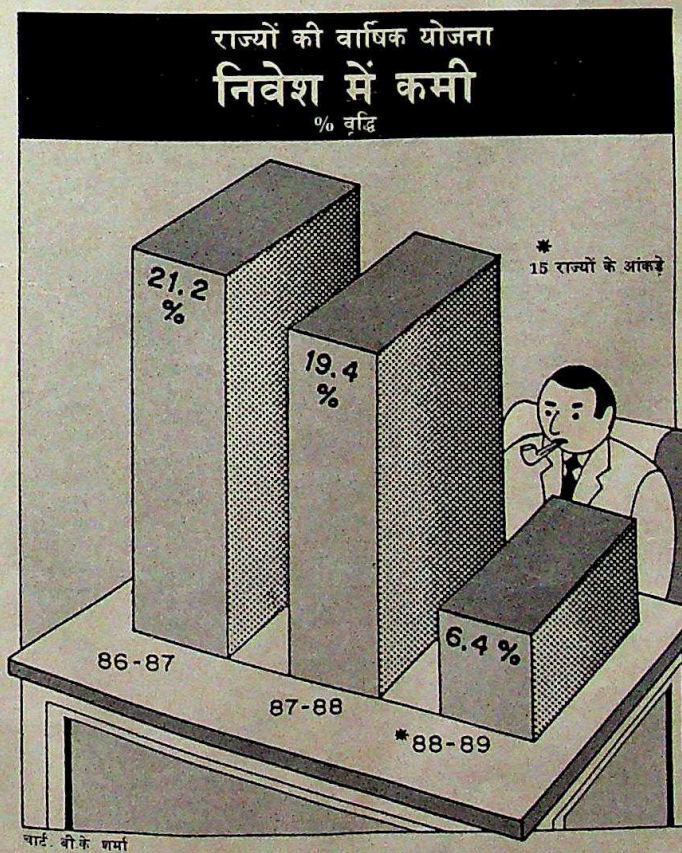

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शेयर बाजार

बजट का साया

अनिश्चित भविष्य का अंदेशा

जब आर्थिक मोर्चे से बुरी खबरें आने लगती हैं और उनके बदतर होते जाने का अंदेशा होता है तो शेयर बाजार में बेचैनी फैल जाती है. सरकारी आंकड़े भी औद्योगिक विकास दर में गिरावट बताने लगें, सरकार की वित्तीय हालत खस्ता हो, कीमतें बेकाबू हो जाएं और हाल के वर्षों के सबसे बुरे बजट का अंदेशा हो तो शेयर बाजार में बेचैनी आना स्वाभाविक ही है.

पिछले पखवाड़े बाजार में जो रौनक आई थी वह अब गायब हो चुकी है. परिणामस्वरूप इकॉनामिक टाइम्स शेयर मूल्य सूचकांक 260 से गिरकर 5 फरवरी को 247.3 पर आ गया. अंदेशा बना हुआ है कि बजट के पहले के तीन हफ्तों में सूचकांक और नीचे जाएगा. जनवरी के शुरू वाली तेजी समाप्त हो गई है और अब अनिश्चित भविष्य का डर एक

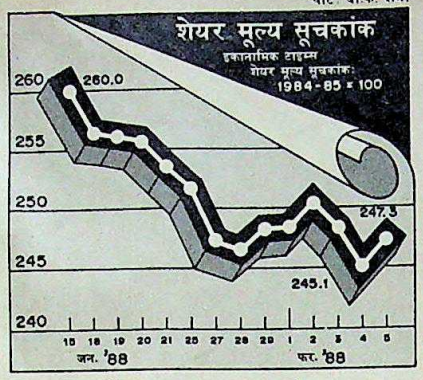

चार्ट: बी.के. शर्मा

बार फिर से जड़ जमा चुका है.

इस दौरान हर क्षेत्र (ऑटोमोबाइल्स, इस्पात, रसायन, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, टायर) के शेयर गिरे. टाटा समूह की दोनों प्रमुख कंपनियों (टिस्को और टेल्को), हिंदुस्तान मोटर्स, रिलायंस और बजाज ऑटो के शेयर भी लुढके.

कंपनियों के कामकाज में सुधार की रिपोर्ट आने के बावजूद ऐसा हुआ. सेंचुरी टेक्सटाइल और सेंचुरी एंका जैसी बड़ी तथा कार्न प्रोडक्ट्स और दीपक नाइट्राइट जैसी छोटी कंपनियों ने भी बेहतर कामकाज और बढ़े लाभांश की घोषणा की. ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, मे ऐंड बेकर तथा फिनोलेक्स केबल्स ने भी बेहतर कामकाज दिखाया है. कई कंपनियों ने विस्तार की भारी-भरकम योजनाएं घोषित कीं. इसमें 200 करोड़ रुपए के विस्तार योजना की घोषणा करने वाली इंडियन एल्यूमिनियम भी शामिल है. निप्पोन डेनरो इस्पात जैसी कंपनियों ने नए इश्यू लाने की घोषणा की.

लगता है कि सरकार को भी उम्मीद है कि 1988 में पिछले साल की तुलना में ज्यादा नई पूंजी बाजार में आएगी. यह शायद 1986 से भी बढ़िया साल साबित हो. लेकिन बाजार में खुशहाली नहीं लौटेगी. बजट से बाजार को बड़ा अंदेशा है. इस वजह से दूसरी गड़बड़ियां फिलहाल परदे के पीछे चली गई हैं. बाजार के कई पंडितों का मानना है कि सरकार इस बजट से शेयर बाजार में जान डालने को उत्सुक है. पर नए करों का बोझ बढ़ेगा. इनमें आय और संपत्ति पर कर बढ़ाना भी शामिल है.

1987 की एक अच्छी बात तो यही है कि पतन का सतत दौर चलने के बावजूद अच्छे शेयर अभी भी बचे हुए हैं पर फिलहाल तो निवेशकों के लिए सबसे अच्छी सलाह यही हो सकती है कि वे पहले देख लें कि बजट कितनी बुरी खबर लाता है.

जमा स्टॉक

	1988 ऊंचा	नीचा	बंद 5.2.88	पखवाड़े में स्टॉक की स्थिति
अशोक लेलैंड	36.50	31.00	32.50	—
एसोसिएटेड सीमेंट	180.00	144.00	158.00	6.00 —
एटलस कोप्को	63.50	49.00	49.00	7.00 —
एशियन पेन्टस्	169.00	147.50	155.00	—
बजाज ऑटो	520.00	435.00	437.50	26.25 —
बड़ौदा रेयॅन	168.00	145.00	152.50	—
बाटा इंडिया	71.50	64.50	66.75	1.00 —
बेयर	320.00	300.00	300.00	5.00 —
भारत फोर्ज	118.00	101.00	108.00	1.00 +
बिरला जूट	44.00	37.75	38.25	2.25 —
ब्लो प्लास्ट	125.00	105.00	108.75	3.75 —
बॉम्बे डाइंग	128.00	94.00	122.00	6.00 +
बुक बांड	87.00	76.00	79.00	4.50 —
ब्रिटानिया इंडिया	109.00	87.50	91.00	6.00 —
सीएट टायर्स	88.00	81.00	88.00	1.50 +
सेंचुरी एंका	1340.00	1080.00	1260.00	70.00 +
क्लोराइड इंडिया	80.50	71.00	73.50	4.50 —
तिरुचिरापल्ली	72.00	61.00	72.00	7.00 +
कोलगेट	220.00	192.50	197.50	6.25 —
डीसीएम	38.25	31.00	33.25	2.50 —
डनलप	83.00	76.75	77.50	3.00 —
एस्कार्ट्स	44.00	40.00	41.75	—
फिनोलेक्स केबिल्स	380.00	311.25	347.50	—
फूड स्पेशिलिटीज	142.00	119.00	120.00	13.00 —
गरवारे नाइलोन	30.00	20.00	25.00	—
जी.ई. शिपिंग	26.35	20.50	23.75	0.60 —
गुजरात स्टेट फर्टि.	118.00	86.50	114.00	2.00 +
ग्रासिम इंडिया	104.75	90.50	91.50	4.00 —
हिंदु. एल्यूमिनियम	139.00	116.00	122.00	2.00 —
हिंदुस्तान कोकोआ	215.00	86.25	90.00	110.00 —
हिंदुस्तान लीवर	81.00	68.50	70.50	3.50 —
हिंदुस्तान मोटर्स	25.00	21.50	21.60	1.20 —
हिंदुस्तान डॉर	212.50	145.00	160.00	17.50 —
आई.ई.एल	43.75	37.00	38.75	1.25 —
इंडियन होटल्स	120.50	100.00	105.00	2.50 +
इंडियन आर्गेनिक	23.00	17.50	19.00	0.75 —
इंडियन रेयॅन	58.00	48.50	50.00	2.00 —
इंद्राल	223.75	180.00	187.50	10.00 —
इंगरसॉल-रैड	335.00	275.00	290.00	5.00 —
आई.टी.सी.	39.75	30.00	33.50	0.75 +
जे.के. सिंथेटिक्स	69.00	55.50	56.00	6.00 —
काइनेटिक इंजी.	185.00	170.00	170.00	7.50 —
किर्लोस्कर क्युमिस	57.50	48.00	57.50	6.50 +
केएसबी पम्प	425.00	365.00	370.00	16.25 —
लारसन-टुब्रो	95.50	77.00	87.00	4.00 —
लिप्टन	67.00	54.00	56.00	4.00 —
लोहिया-मशीन्स	13.50	9.50	10.00	1.00 —
महिंद्रा-महिंद्रा	63.00	52.00	57.00	1.50 —
मैकडोवेल	83.50	72.50	76.50	1.50 —
मोटर इंडस्ट्रीज	587.50	490.00	520.00	20.00 —
मुकुंद आयरन	85.00	75.00	78.50	1.50 —
नेशनल आर्गेनिक	525.00	435.00	450.00	20.00 —
निरलॉन	8.75	5.00	6.50	1.50 +
ओरके सिल्क मिल्स	30.00	22.00	23.50	2.50 —
पेट्रको इलेक्ट्रॉनिक्स	33.75	26.00	27.50	2.00 —
ओसवाल आयो	134.50	111.50	114.50	4.50 —
ओटिस एलिवेटर	215.00	190.00	207.50	7.50 +
प्रीमियर ऑटो	31.00	24.50	26.50	0.75 —
रैनबेक्सी	102.50	78.00	90.00	1.00 +
रेमंड	96.00	44.00	48.00	43.00 —
शॉ वैलेस	132.00	114.00	114.00	8.00 —
रिलायंस इंडस्ट्रीज	117.00	98.00	99.00	7.00 —
रिचर्डसन हिंद	305.00	260.00	285.00	10.00 +
श्रीराम फाइबर्स	42.75	34.00	34.00	5.00 —
एसकेएफ बियरिंग्स	1315.00	1058.00	1280.00	80.00 +
सीमेन्स इंडिया	80.00	71.00	75.00	1.00 —
स्पिक	37.00	28.50	32.50	1.25 —
टाटा स्टील	685.00	595.00	613.75	35.00 —
टेल्को	400.00	355.00	362.50	12.50 —
विम्को	24.00	20.00	20.75	0.75 —

भारतीय रुपए का मूल्य

देश	मुद्रा	इकाई	भुगतान के लिए (रुपए)	वसूली के लिए (रुपए)
आस्ट्रेलिया	डालर	1	9.3763	9.2773
आस्ट्रिया	शिलिंग	1	1.1039	1.0921
बहरीन	दीनार	1	34.8832	34.5014
बांग्लादेश	टका	100	42.6932	42.5116
कनाडा	डालर	1	10.4017	10.2951
डेनमार्क	क्रोनर	1	2.0289	2.0074
मिस्र	पौंड	1	9.3900	9.3136
फ्रांस	फ्रैंक	1	2.3310	2.2772
हांगकांग	डालर	1	1.6923	1.6754
इंडोनेशिया	रुपिया	100	0.0783	0.0774
ईरान	रियाल	100	19.3220	19.2010
इटली	लीरा	100	1.0532	1.0311
जापान	येन	100	10.30	10.15
केन्या	शिलिंग	1	0.7730	0.7448
कुवैत	दीनार	1	47.4910	47.4014
मलेशिया	डालर	1	5.1482	5.0855
मारीशस	रुपया	1	1.0326	1.0200
नेपाल	रुपया	1	0.6250	0.6200
हालैंड	गिल्डर	1	6.9012	6.7413
पाकिस्तान	रुपया	1	0.7630	0.7489
सिंगापुर	डालर	1	6.5471	6.4322
स्पेन	पेसो	1	0.1147	0.1088
श्रीलंका	रुपया	1	0.4310	0.4185
स्वीडन	क्रोनर	1	2.1724	2.1570
स्विट्जरलैंड	स्विस फ्रैंक	1	9.4569	9.1437
तंजानिया	शिलिंग	1	0.1530	52.6830
थाईलैंड	बहत्त	100	52.7532	22.8452
ब्रिटेन	पौंड	1	22.9750	13.9653
सं. राज्य अमेरिका	डालर	1	13.1925	3.5871
सं. अरब अमीरात	दिरहाम	1	3.5832	21.5225
सोवियत संघ	रूबल	1	21.8530	7.4864
पश्चिम जर्मनी	जर्मन मार्क	1	7.8678	

स्रोत—बैंक ऑफ टोक्यो, नई दिल्ली, 9.2.88

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सही दुल्हन की तलाश...
सौ साल पहले.

लाला दीनदयाल, हैदराबाद के एल्बम से: सौ साल से भी अधिक पुरानी तस्वीर

जिसकी जीती-जागती याद आज भी हमारे साथ है.
शुक्रिया ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोटोग्राफ़ी का!

अपने पारिवारिक एल्बम के कुछ पन्ने पलटाकर देखिए...
जिनमें सजी हैं बरसों पुरानी यादों को संजोए चंद तस्वीरें!
ब्लैक एण्ड व्हाइट में. साठ, सत्तर, अस्सी बरस... या शायद इससे भी पुरानी, पर आज भी नज़र आती हैं उतनी ही साफ़-स्पष्ट और ज्यों की त्यों.
इसलिए जब भी आप किसी नाज़ुक लम्हे की मीठी याद कैमरे में कैद करना चाहें तो ब्लैक एंड व्हाइट फ़िल्म ही इस्तेमाल करें.
जिन्हें एक बार खींचकर, आप बरसों नाज़ करेंगे.

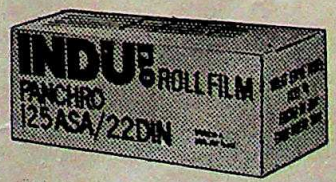

वक़्त, यादों को भले ही धुंधला कर दे...
पर ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें कभी धुंधली नहीं होतीं.

इंदु
INDU

इंदु ब्लैक एंड व्हाइट
रोल फ़िल्म और ब्रोमाइड.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar Sista's-HPF.835.87.HIN-B

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सूरजकुंड मेला

लोक कलाओं का झरोखा

देश के कोने-कोने से आए हस्तशिल्पियों का अनूठा संगम

पांडिचेरी से आए मूर्तिकार राजू शिल्पी के लिए पिछला पखवाड़ा बहुत भाग्यशाली रहा. सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले के लिए घर से निकलते समय वे अपने साथ पत्थर की मूर्तियों का जो विशाल भंडार लेकर चले थे उसकी बिक्री धड़ल्लेदार रही. पिछले साल पहली बार इस मेले में आते समय वे यह कल्पना भी नहीं कर पाए थे कि उनकी सभी मूर्तियां पहले तीन दिन में ही बिक जाएंगी.

राजू शिल्पी जैसा ही अनुभव लगभग उन सभी 150 हस्तशिल्पियों का रहा जो 1 से 15 फरवरी तक दिल्ली के निकट सूरजकुंड पर्यटन स्थल पर आयोजित दूसरे राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में भाग लेने के लिए इकट्ठा हुए थे. केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय, हरियाणा पर्यटन विभाग, केंद्रीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा विभाग ने मेला आयोजित किया था.

दर्शकों के लिए मेले का एक अन्य खास आकर्षण यह था कि पूरे वातावरण पर ठेठ ग्रामीण वातावरण की गहरी छाप थी—पनघट पर रखे घड़े; कच्चे नाले के दोनों ओर अलग-अलग प्रांतों की झोंपड़ियों में लगी परंपरागत हस्तशिल्प की दुकानें; उनमें काम करते हुए हस्तशिल्पी; 'चौपाल' पर बिछी विशालकाय चारपाई पर हुक्का गुड़गुड़ाते हुए लोग; रागिनी गाते हुए, कच्ची घोड़ी नचाते हुए और विभिन्न प्रदेशों के नृत्य पेश करते हुए कलाकार; तथा कच्ची पगडंडियों के चौराहों पर रीछ, सांप और भालू के तमाशे दिखाते हुए मदारी को घेरे खड़े बच्चे.

मेले में बुलाए गए अधिकांश शिल्पी केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा पुरस्कृत शिल्पी थे. उनमें से कई लोग भारत महोत्सवों के कारण अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ जैसे देशों की यात्राएं कर चुके हैं तथा बड़े मेलों में सरकारी प्रश्रय के कारण अपेक्षाकृत समृद्ध हस्तशिल्पियों में गिने जाने लगे हैं. मगर इसके बावजूद उनसे होने वाली छोटी-सी अंतरंग बातचीत भी उनके दुख-दर्द और असहायता के दर्शन कराने के लिए काफी है.

सीतामढ़ी से आई कुमुदनी देवी सिक्की घास से टोकरियां और सजावट की दूसरी कई चीजें बुनती हैं. घास से बुनी गई दुर्गा प्रतिमा के लिए उन्हें 1971 में राष्ट्रीय शिल्पी पुरस्कार मिल चुका है. उनके साथ आई उनकी बेटी वैदेही देवी को 1983 में मधुबनी पेंटिंग के लिए मेरिट सर्टिफिकेट मिला था. पिछले साल कुमुदनी देवी भारत महोत्सव के सिलसिले में अमेरिका गई थीं जहां उन्हें अपने कला प्रदर्शन के लिए हर रोज 20 डॉलर मिलते थे. वहां से लौटते समय उनके पास 3000 डॉलर जमा हो चुका था. गांव आते ही उन्होंने इस पैसे से दो 'कट्ठा' घर बनाने वाली जमीन खरीद ली और बाकी पैसे से 13 कट्ठा (लगभग सवा एकड़) धान वाली जमीन बंधक ले ली. अपने झोंपड़ीनुमा स्टाल पर बीसियों तरह की रंगबिरंगी कलाकृतियों से घिरी बैठीं दोनों महिलाएं इस बात से संतुष्ट थीं कि किसी जमाने में उनके इलाके तक सीमित इन दोनों कलाओं को अब राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता मिल रही है और विदेशों में भी नई संभावनाएं दिखाई देने लगी हैं.

लेकिन इस काम से जुड़ी समस्याएं गिनाते हुए कुमुदनी देवी कहती हैं, "जंगल में सिक्की बीनते-बीनते कमर दोहरी हो जाती है. फिर घास की छंटाई, छिलाई और रंगाई करने के बाद चीजें बनाई जा सकती हैं. यह सारी मेहनत करने के बाद भी लड़कियों को महीने में 200 रुपए से ज्यादा नहीं मिल पाता."

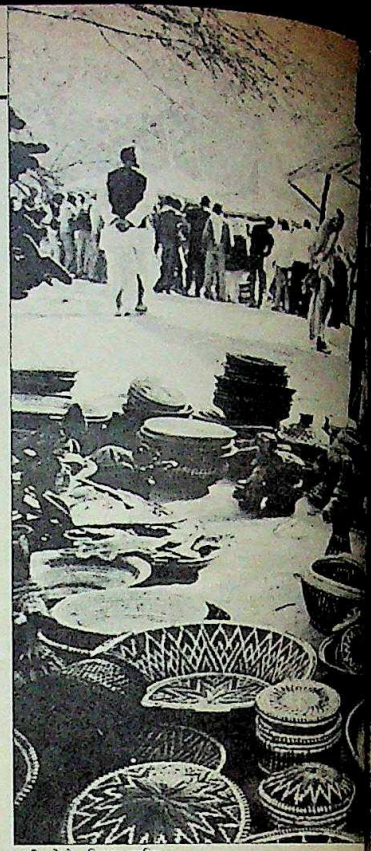

सभी फोटो: विजय क्रांति

जयपुर से आए कोटा साड़ी बुनकर अब्दु वहीद रेशम और सूत के ताने-बाने में ब बार आकर फंसने वाले पत्तों और धूल परेशान थे. मेले के दौरान बुनकर लटक हुई साड़ी शाम की धूप में सुनहरी चमक कर रही थी. लेकिन अपने धंधे के प्रति अ का नजरिया इस चमक से ठीक उलटा प पेश कर रहा था, "दिन भर अड्डे पर ब खाने के बाद दो आदमी मुश्किल से आ साड़ी बुन पाते हैं. इतना हाड़-मांस खपाने भी एक आदमी दिन भर में 9-10 रुप ज्यादा नहीं कमा सकता. असली कमाई सेठिया (व्यापारी) लोगों की होती है

चक्की पीसती बांवरीः मेले का सुख

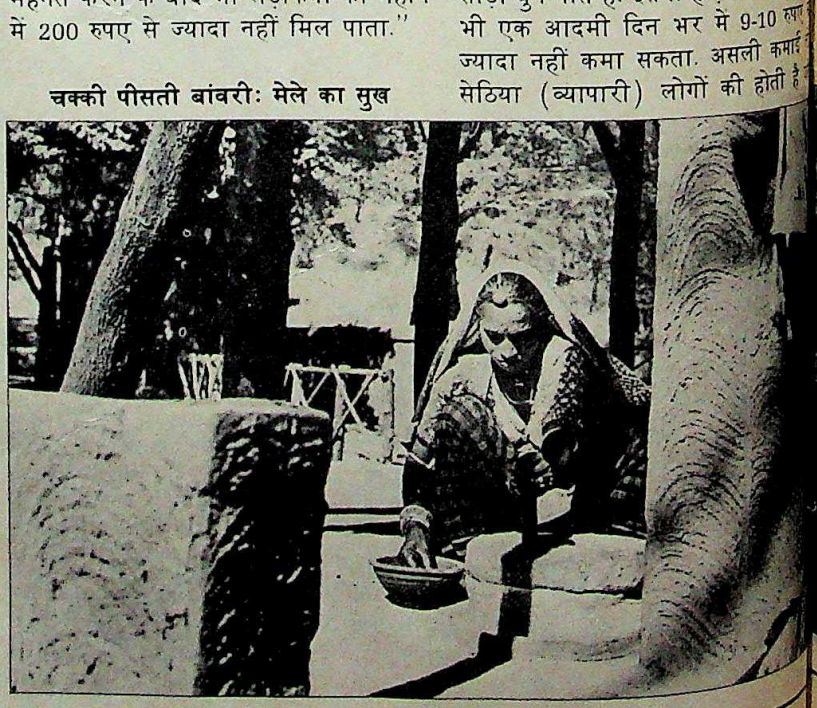

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

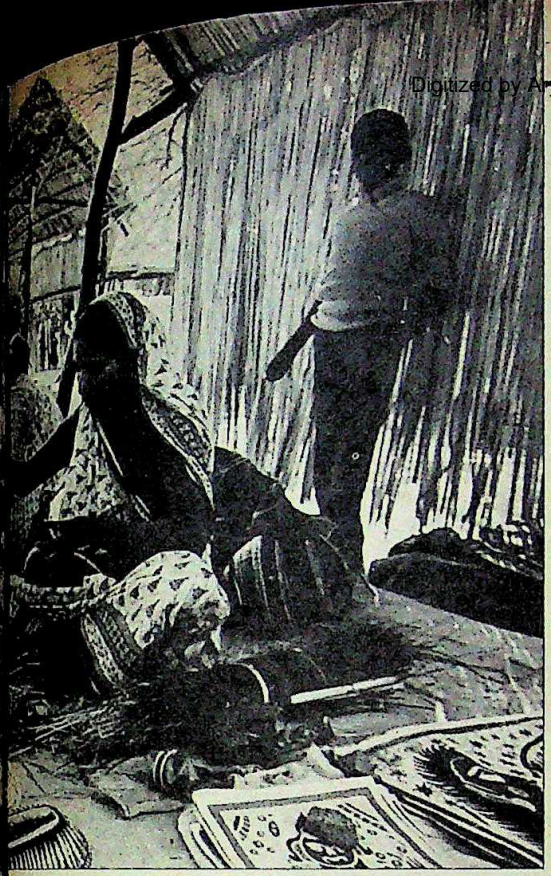

सिक्की घास से टोकरी बनाती वैदेही देवी: समृद्धि का नया द्वार

तो यह है कि आने-जाने और रहने का किराया सरकार देती है और मशहूरी होने के साथ-साथ बिक्री भी बढ़िया हो जाती है."

सरकंडे वाली छत के नीचे मिट्टी के चबूतरे पर बैठे राजू शिल्पी ग्रीनस्टोन की एक गणेश प्रतिमा की सफाई में लगे थे. पांडिचेरी सरकार से मास्टर-क्राफ्ट्स-मैन पुरस्कार से सम्मानित राजू अपने यहां कुछ लड़कों को पत्थर तराशना भी सिखाते हैं. गणेश, लक्ष्मी, शिव, सरस्वती और अप्सरा की मूर्तियों के ढेर की ओर इशारा करते हुए उनका कहना था, "पिछले साल मेले में पता चला कि यहां के लोग देवी-देवताओं की मूर्तियां ज्यादा पसंद करते हैं. इसलिए पिछले तीन महीने में मैं और मेरे लड़के ऐसी ही मूर्तियां बनाते रहे ताकि अच्छी बिक्री हो."

मगर मेले में भाग लेने वाले कुछ लोगों की खुशी का सबसे बड़ा कारण यह था कि मेले के हालात उन हालात से कहीं बेहतर थे जिनमें उन्हें हर रोज रहना पड़ता है. मेले में कठपुतली दिखाने वाले, कच्ची घोड़ी नचाने वाले, रीछ वाले और नट के करतब दिखाने वाले कलाकारों में से अधिकांश कलाकार दिल्ली में शादीपुर बस डिपो के सामने बसी झुग्गी-झोंपड़ी बस्ती से लाए गए थे.

कच्ची घोड़ी और कठपुतली के साथ गीत गाने वाली 20 वर्षीया बतासी इसी बस्ती में पैदा होकर बड़ी हुई है. उनके परिवार के लोग परिवार कल्याण कार्यक्रम और यूनीसेफ कार्यक्रमों के प्रचार के लिए कठपुतली, कव्वाली, लोकनृत्य आदि पेश करते हैं. इनमें से कई लोग अमेरिका और सोवियत संघ के भारत समारोहों में भी होकर आए हैं. मेले के दौरान शिल्पियों की तरह इन कलाकारों के लिए भी सूरजकुंड के पर्यटक निवास में रहने और भोजन की व्यवस्था की गई थी. बतासी के लिए खुशी की सबसे बड़ी बात यह थी कि उनकी बस्ती में कई सौ झुग्गियों के लिए एक नलका है जबकि मेले वाले घर में नहाने के लिए बाथरूम भी उपलब्ध था और जगह साफ सुथरी थी.

बतासी की तरह ही 60 रुपए दिहाड़ी के हिसाब से काम करने वालों में विख्यात वयोवृद्ध कठपुतली कलाकार मालूराम भट भी थे जो दर्जनों देशों में अपनी कला का प्रदर्शन करने के बाद अभी भी शादीपुर डिपो बस्ती में रहते हैं. वे अपने 18 वर्षीय बेटे प्रभु, बहू और पोती को भी लाए हुए थे.

मेले के लिए बनाए गए गांव के मुख्य द्वार में घुसते ही सबसे पहला 'घर' नागौर के बांवता गांव की 55 वर्षीया बांवरी का था जो दर्शकों को चक्की पीसकर और घर की लिपाई करके दिखा रही थीं. बांवरी के लिए खुशी की बड़ी बात यह थी कि "मेले का मेला हो गया और साठ रुपया दिहाड़ी भी मिल गई. गांव में तो रोज मुंह अंधेरे में पांच-छह किलो अनाज पीसना होता है और यहां सिर्फ एक-दो किलो. मेले की मौज अलग से."

मगर मेले के अवसर का लाभ केवल शिल्पियों और पर्यटन को ही मिला हो, ऐसा नहीं. बंधुआ मजदूर संघ के नेता स्वामी अग्निवेश ने इस मौके का इस्तेमाल अखबारों की सुर्खियों में अपनी बात कहने के लिए किया. 5 फरवरी के दिन निकटवर्ती पत्थर खदानों और क्रशरों के लगभग 100 मजदूरों का जुलूस लेकर वे शिल्प ग्राम के भीतर तक घुस आए और लोगों व अखबारों का ध्यान अपनी मांगों की ओर आकर्षित किया.

और जहां तक मेले में आने वाले दर्शकों की बात है, उनके लिए देश के कोने-कोने से आए प्रमुख भारतीय हस्तशिल्पों को देखने, खरीदने और शिल्पियों को काम करते हुए अपनी आंखों देखने का यह एक ऐसा अवसर था जो आम तौर पर किसी एक जगह संभव नहीं होता.

—विजय क्रान्ति

धागा देकर ठेके पर बुनाई करवाते हैं." इसलिए मैं तो अपने बेटे को साड़ी बुनने के बजाय दर्जी बनाने की सोच रहा हूं."

लेकिन मेले में ऐसे शिल्पकारों की भी कमी नहीं थी जिनके लिए इस तरह के मेलों ने किस्मत के नए दरवाजे खोल दिए हैं. श्रीनगर से अपने साथ पेपरमैशी का ढेर सारा सामान लाए हुए नजीर अहमद (27) ग्राहकों की अच्छी-खासी भीड़ से घिरे हुए थे. इन दिनों उनके बड़े भाई मास्को में भारत महोत्सव के सिलसिले में अपने सामान की बिक्री और प्रदर्शन के लिए गए हुए हैं. उनका कहना था, "इस तरह के मेले का बड़ा फायदा

राजू शिल्पी: पत्थर से चांदी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तमस

विवादों की चांदमारी

क्षुद्र राजनैतिक स्वार्थों ने विवाद को सड़कों पर ला पटका

दूरदर्शन के महानिदेशक भास्कर घोष कहा करते थे कि तमस (अंधेरा) को आने दीजिए फिर हर ओर रोशनी हो जाएगी. भारत विभाजन की घटनाओं पर बने गोविंद निहलाणी के इस विवादास्पद सीरियल को राष्ट्रीय प्रसारण के लिए मंजूरी देते वक्त उन्होंने शायद सोचा भी नहीं होगा कि इसे लेकर इतना बवाल खड़ा हो जाएगा. तमस ने रोशनी ही नहीं हो-हल्ला भी पैदा किया. वह भी दिल्ली, बंबई और हैदराबाद जैसे शहरों में जहां पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलानी पड़ीं.

इन सुर्खियों ने लोगों का ध्यान लाखों टीवी दर्शकों के घरों में चुपचाप हो रहे बदलाव से हटा दिया. राजनैतिक दलों के सख्त रवैये और प्रचार की चकाचौंध से दूर इन घरों में एक बहस शुरू हो गई थी. तमस में दिल दहला देने वाली उन्मत्त हिंसा के दृश्य हैं जिन्हें देखकर हैरत में पड़े लोग यह सवाल पूछने लग गए कि क्या यह देश सांप्रदायिकता के खड्डे में गिरने जा रहा है.

देश में ही नहीं, सरहद के उस पार भी तमस अखबारों के लिए एक सनसनीखेज मामला था. हाल के दिनों में बोफोर्स और श्रीलंका के किसी भी मुद्दे को भारतीय अखबारों और पत्रिकाओं में इतनी जगह नहीं मिली जितनी तमस के इस तमाशे को. सरहद के पार पाकिस्तानी अखबारों ने भी प्रदर्शनों की खबरें छापीं और संपादकीय टिप्पणियों में लिखा कि तमस ने जो सचाई प्रस्तुत की है उससे भारत के हिंदू पुनरुत्थानवादी खतरा महसूस करने लगे हैं.

तमस के गुणों-अवगुणों के बारे में कोई कुछ भी सोचे पर इसके दृश्यों से दिमाग पर पड़ने वाले असर से इनकार नहीं किया जा सकता. यह सीरियल दिल को कचोटता है और दिमाग को झकझोरता भी है. बुरी तरह चकराए हुए आप यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसी घटनाएं आखिर क्यों होती हैं. यह भयभीत भी करता है और चेतावनी देता है कि यह सब कुछ फिर घट सकता है—आपके पड़ोस में, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ या फिर खुद आपके साथ.

देर रात तक तमस देखने के लिए जागते रहने वाले बच्चे अपनी आंखों से इस डर को महसूस करते हैं. सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट रघुवीर मल्होत्रा के 10 वर्षीय बच्चे ने तीसरे भाग में जब हत्याओं का दृश्य देखा तो उसे उल्टी आ गई और वह बीमार पड़ गया. लेफ्टिनेंट कर्नल मनोहर सिंह ने दिल्ली के एक अखबार को शिकायत करते हुए लिखा कि वे तमस देखने के बाद सो नहीं सके. ज्यादातर लोग तमस को सिर्फ 1947 की घटनाओं के रूप में ही नहीं देखते. वे इनमें 1972 के भिवंडी, 1984 के दिल्ली, 1987 के मेरठ का अक्स भी देखते हैं.

विवाद तमस के सबक से ही पैदा हुआ. एक तरफ वे लोग हैं जो चाहते हैं कि इस सीरियल ने उपमहाद्वीप की सबसे शर्मनाक घटना के दृश्यों को दिखाकर 1947 के घाव ताजा कर दिए हैं. आलोचकों के हिसाब से इसमें हिंसा और अमानवीयता की भरमार दिखाई देती है. दिल्ली में हुई प्रगतिशील लेखक संघ की एक बैठक में मल्होत्रा की शिकायत थी कि, "पहले ही भाग से तमस में उन्माद का चित्रण किया गया है. मैं नहीं मानता कि इसमें कोई सबक भी प्रस्तुत किया गया है." भारतीय जनता पार्टी और शिव सेना सरीखे राजनैतिक दल तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और आर्य समाज जैसे संगठन (जो 1947 में हिंदू सांप्रदायिकता के अग्रदूत थे), इसका जोरदार विरोध कर रहे हैं.

तमस का एक दृश्य और (नीचे) दिल्ली में भाजपा का विरोधः जोरदार प्रदर्शन

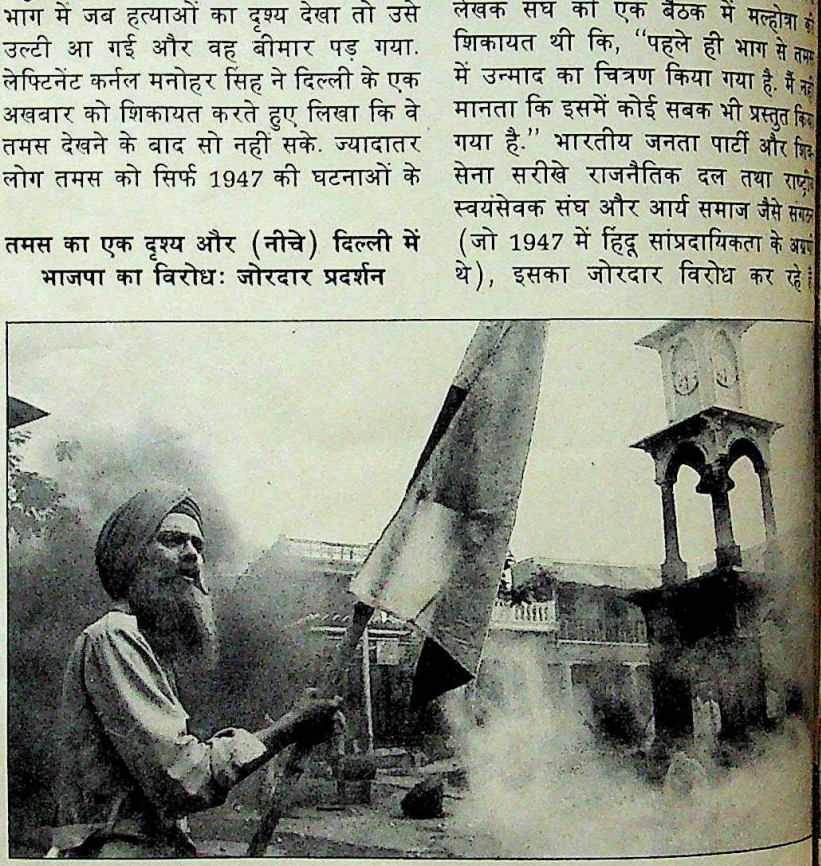

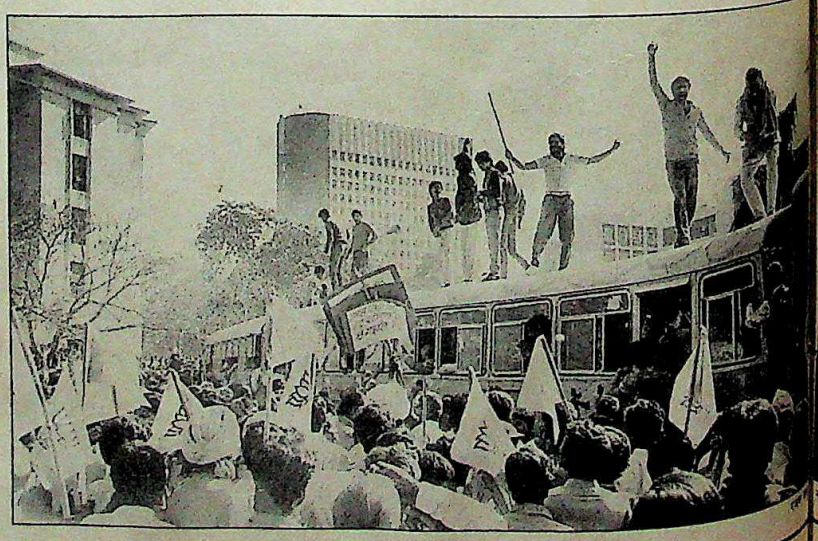

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शिवसेना नेता प्रमोद नावलकर को शिकायत है कि इसमें मुसलमानों की तरफदारी की गई है. भाजपा अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी के मुताबिक, "इसमें इतिहास को विकृत रूप में पेश किया गया है." उनका कहना है कि संघ और आर्य समाज को तो 'बर्बर कट्टरता-' वादियों' जैसा दिखाया गया है जबकि मुस्लिम लीग वालों को 'सिर्फ गुंडे' मानकर ही छोड़ दिया गया है और कांग्रेसियों को 'महज गोबर गणेश' की भांति पेश किया गया है.

घोष इन आरोपों को सही नहीं मानते. उनका कहना है कि धारावाहिक सिर्फ सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वालों को ही नहीं दर्शाता, निहलाणी के सधे हाथों में पड़कर वह सब चीजें बहुत कुछ कह जाती हैं और सांप्रदायिकता काफी घृणित दिखाई देने लगती है– भले ही उसका पोषण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और आर्य समाज की ओर से हुआ हो या मुस्लिम लीग की ओर से.

इस तमाम हो-हल्ले के बावजूद निहलाणी खुश हैं कि तमस ने सांप्रदायिकता पर एक बहस तो शुरू की. तमस बनाना उनके लिए एक थका देने वाला अनुभव था. इसे पूरा कर लेने के बाद उनमें जरा भी भावुकता नहीं बची. पर व्यावसायिक तौर पर वे संतुष्ट हैं. वे कहते हैं, "मैं तमस को अपनी सबसे यथार्थपरक कृति मानता हूं." इसे अब शायद दो भागों की फीचर फिल्म के रूप में भी रिलीज किया जाएगा.

भीष्म साहनी भी इतने ही संतुष्ट हैं. प्रकाशक अब उनकी टोह में रहते हैं. वे तमस को फिर से छापने की अनुमति चाहते हैं. उनसे इसी विषय पर और उपन्यासों का तकाजा भी किया जा रहा है.

साहनी खिल्ली उड़ाते हुए कहते हैं, "मुझे परवाह नहीं कि कट्टरवादी तमस को किस नजरिये से देखते हैं. आम पाठकों और दर्शकों की प्रतिक्रिया कुल मिलाकर अच्छी है. मुझे तमस के किसी शब्द या अक्षर तक के लिए पछतावा नहीं है."

हैदराबाद दूरदर्शन में तोड़फोड़ और (नीचे) तमस को कलाकारों का समर्थन

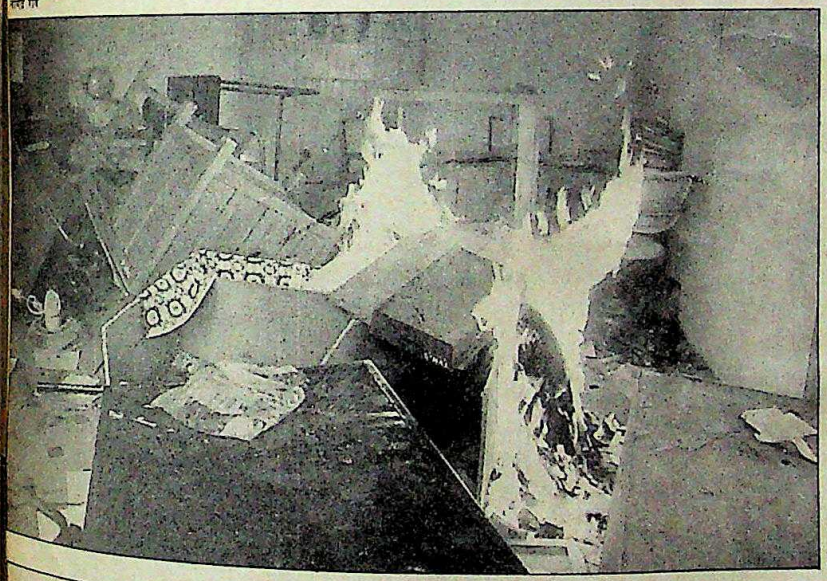

पर आम दर्शक तमस के बारे में क्या कहते हैं? दिल्ली पब्लिक स्कूल, आर.के. पुरम के 11वीं कक्षा के 65 छात्रों के एक सर्वे से पता चलता है कि सिर्फ सात लड़के इसे बंद करने के पक्ष में थे. क्योंकि इसमें काफी हिंसा दिखाई गई है. तकरीबन इन सभी छात्रों की समझ में तमस 'सांप्रदायिक हिंसा की व्यर्थता का सबक' सिखाता है.

अन्यत्र भी नौजवान इस धारावाहिक का संदेश अच्छी तरह समझ रहे हैं. बस्ती निजामुद्दीन की छात्रा निशात और सत्यवती गर्ल्स स्कूल में उसके साथ पढ़ने वाली छात्राओं का ही उदाहरण लीजिए. वे कहती हैं, "हमने यह सीखा कि भड़काने वाले तत्वों के बहकावे में न आएं." उसकी मां अफरोज को प्रदर्शनकारियों पर गुस्सा आता है. वे पूछती हैं, "पहले वे हर रोज हो रही हत्याओं को क्यों नहीं रोकते?"

पर कम पढ़े-लिखे मुसलमानों को तमस दिखाए जाने की बुद्धिमता पर संदेह है. दुकानदार जहीर अहमद कहते हैं, "यह बात अहम नहीं कि यह सब हुआ था या नहीं पर इसे दिखाने से गड़बड़ी का अंदेशा है."

हर किसी के लिए तमस का एक अलग अर्थ है. जहां यह कुछ लोगों की आशंकाओं की पुष्टि करता है, वहीं कुछ दूसरों को अपने पूर्वाग्रहों का अंतरनिरीक्षण करने के लिए बाध्य भी करता है. संघ के समर्थक कहते हैं कि धारावाहिक में यह दिखाया गया है कि हिंदुओं की रक्षा सिर्फ संघ ने ही की थी. एक आला सरकारी अफसर कुछ और ही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सिख-मुस्लिम दंगों से पंजाब के आतंकवादी यह समझ जाएंगे कि पाकिस्तान का मुस्लिम नेतृत्व कभी भी उनका दोस्त नहीं हो सकता.

दूरदर्शन के लिए, तमस बदलाव की शुरुआत हो सकता है. घोष मानते हैं, "हम इस हालत में पहुंच गए हैं कि सामाजिक मसलों पर कई और इतने ही दमदार कार्यक्रम तैयार कर सकें." अमेरिका में टेलीविजन देखने वाली '60 के दशक की पीढ़ी ने वियतनाम में हो रही हत्याओं की अनावश्यकता को जैसे समझा था, ठीक वैसे ही हो सकता है तमस हिंदुस्तान के दर्शकों को सांप्रदायिक हिंसा की निरर्थकता का एहसास दिलाए. अगर ऐसा हुआ तो तमस अपने मकसद में कामयाब होगा.

—**रौनक सिंह** और बंबई से एम. रहमान

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

क्रिकेट

मैदान के बाहर मुकाबला

वेंगसरकर की होशियारी से एक अभूतपूर्व विवाद संभला

टाइम्स ऑफ इंडिया के पहले पेज पर आर.के. लक्ष्मण के एक कार्टून में बच्चे एक नये तरह का खेल खेल रहे हैं जो बोर्ड और खिलाड़ियों के बीच है. इसमें वे बल्ले और विकेट से एक-दूसरे पर आक्रमण कर रहे हैं. पिछले कुछ समय से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और खिलाड़ियों में काफी तनातनी चल रही थी और अब खिलाड़ी और अधिकारी एक-दूसरे के खिलाफ जमते लग रहे हैं.

जब वेस्ट इंडीज टीम का दौरा चल रहा था तब बोर्ड ने खिलाड़ियों के खिलाफ कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की जबकि खिलाड़ियों का करिश्मा घटिया प्रदर्शन की वजह से धुंधलाने लगा था. वेस्ट इंडीज टीम के जाते ही वैसे ही जो प्रश्न टलता आ रहा था उसका जवाब मिल गया कि क्या बोर्ड अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके भारतीय कप्तान दिलीप वेंगसरकर को खिलाड़ियों के समाचारपत्रों में कालम न लिखने के अनुबंध की अवहेलना के लिए दंडित कर सकेगा?

इसी सिलसिले में पिछले पखवाड़े क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की बंबई में हुई विशेष बैठक में वेंगसरकर के कदम को अनुबंध की स्पष्ट अवज्ञा करार दिए जाने से सभी अचंभित रह गए. सजा के बतौर स्टार बल्लेबाज पर 10,000 रुपए जुर्माना और छह महीनों के लिए क्रिकेट प्रतिस्पर्द्धाओं में खेलने पर रोक लगा दी गई. क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने वेंगसरकर के निष्कासन की अवधि जानबूझकर ऐसी चुनी जिससे वह केवल द्वितीय श्रेणी की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं, इस महीने के आखिर में बंगलादेश में होने वाले एशिया कप और मार्च में शरजाह टूर्नामेंट से वंचित रहें.

हर किसी को लग रहा था कि वेंगसरकर के समर्थन में अन्य क्रिकेट खिलाड़ी विरोधस्वरूप संयुक्त कार्रवाई करेंगे. लेकिन क्रिकेट बोर्ड इससे एक कदम आगे निकला और उसने स्पष्ट कर दिया कि जो खिलाड़ी एशिया कप में किसी बेबुनियाद कारण से अनुपस्थित रहेगा उसके चयन पर पूरे एक साल के लिए रोक लगा दी जाएगी. इस धमकी के बावजूद खिलाड़ियों ने एक संयुक्त विरोध पत्र पर हस्ताक्षर किए और इसे वेंगसरकर को सौंप दिया.

एक समय ऐसा लगने लगा था कि भारतीय क्रिकेट में भारी उठापटक होने जा रही है. लेकिन जब सीधे तकरार की नौबत आने लगी तब वेंगसरकर ने दूर दृष्टि का

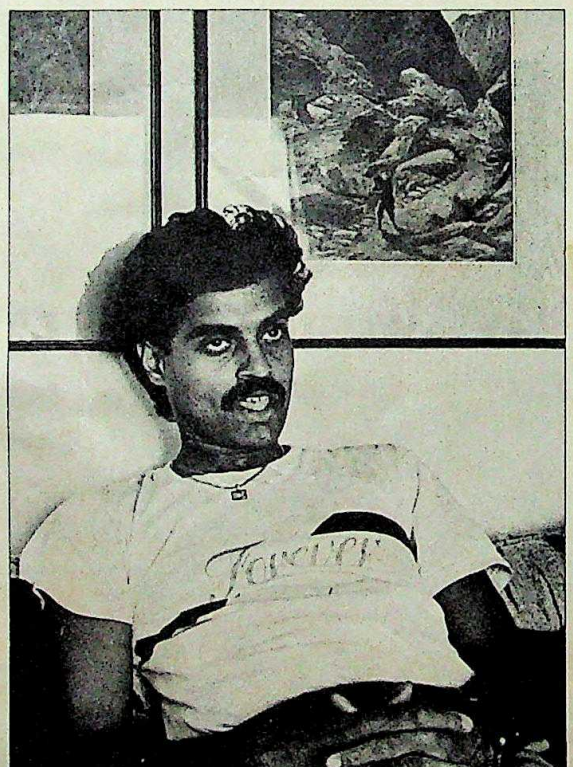

वेंगसरकर: कुछ नहीं जानता

परिचय देते हुए अपने कदम पीछे खींच लिए. उन्होंने कहा, "मेरी पूरी टीम खेल का तब तक बहिष्कार करना चाहती थी जब तक कि मैं बहाल न हो जाता और उसने इस संबंध में लिखित वक्तव्य भी दिया. लेकिन मैं इस झमेले में खिलाड़ियों को शामिल नहीं करना चाहता."

खेल के मैदान के बाहर हुआ यह नाटकीय घटनाक्रम भारतीय क्रिकेट के एक अध्याय समाप्ति का सूचक है. खिलाड़ियों ने क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों का निरादर किया और उन पर वाहवाही और धन की बरसात होती रही. पूर्व टेस्ट खिलाड़ी एम.एल. जयसिम्हा के कथन से पूर्व खिलाड़ियों और अधिकारियों के सोच की झलक मिलती है. उन्होंने कहा, "खिलाड़ी पिछले कुछ सालों से जो मर्जी आए करते रहे और वेंगसरकर पर प्रतिबंध के बोर्ड के फैसले से उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई है."

विडंबना यह है कि क्रिकेट बोर्ड का दृढ़ फैसला ऐसे समय आया है जब उसने स्वयं अनुशासन और संगठनात्मक एकता की कमी प्रदर्शित की है. किसी समय देश की सर्वश्रेष्ठ समझी जाने वाली यह खेल संस्था पिछले साल से विभिन्न विवादों का केंद्र बन गई है. इसमें चयन समिति का अचानक बदला जाना, उदयपुर में रिलायंस कप के पहले प्रशिक्षण कैंप लगाना और हटाना, वेस्ट इंडीज टेस्ट मैच के दौरान टीम के फिजियोथेरेपिस्ट का निकाला जाना और फिर उसकी वापसी, विकेटकीपर किरण मोरे को टीम में शामिल न किया जाना और भारत-वेस्ट इंडीज के बीच अहमदाबाद में खेले गए एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच के स्तर के संबंध में अंत तक भ्रांति बने रहना आदि शामिल है.

यहां तक कि खिलाड़ियों द्वारा कालम लिखे जाने के प्रश्न को भी वेंगसरकर के खिलाफ दिखाई गई अचानक सख्ती के पहले कभी ठीक तरह से नहीं निबटाया गया. पूर्व टेस्ट चयनकर्ता हनुमंत सिंह का कहना था, "यही समय था जब बोर्ड अपने अधिकार को कायम कर सकता था, लेकिन यदि सही कदम सही समय पर उठाया जाता तो इस घालमेल वाली स्थिति को टाला जा सकता था."

वेंगसरकर के जंग का विषय जारी न रखने के फैसले ने भारतीय क्रिकेट को बचा लिया. अब आम चर्चा यह है कि क्या इस स्टार बल्लेबाज को शरजाह दौरे में शामिल किया जाएगा या कम-से-कम घरेलू क्रिकेट खेलने की अनुमति प्रदान कर दी जाएगी. और इसी बीच कप्तानी की पंक्ति में खड़े रविशास्त्री से ढाका में होने वाले एशिया कप में एक बार फिर भारतीय क्रिकेट टीम की कमान संभालने को कहा गया है.

—एम. रहमान

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आम आदमी के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक उत्थान की कहानी-उपलब्धियों की जबानी

10 जनवरी। कर्नाटक की वर्तमान सरकार की 5वीं जयंती। एक गतिशील और जिम्मेदार सरकार जिसने केवल 5 वर्षों में अपनी मूलभूत और रचनात्मक नीतियों के कारण कर्नाटक का नक्शा ही बदल दिया है। इन प्रगतिशील नीतियों से आम आदमी को बहुत राहत पहुंची है। एक सरकार जिसने विगत 5 वर्षों के दौरान अभूतपूर्व भयंकर सूखे के बावजूद अपने अधिकांश वायदे पूरे कर दिखाए हैं तभी तो कर्नाटक हर मामले में देश का एक आदर्श राज्य माना जाता है।

जीवन स्तर पहले से बेहतर

वर्तमान सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले दिन से ही पददलितों के उत्थान वाली योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने तथा निर्धन लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कमर कसी थी। इस सरकार के पहले कार्यों में एक था- न्यूनतम दैनिक मजदूरी को 7 रु. से बढ़ाकर 12 रु. कर देना। इसके साथ-साथ ही आशाकिरण (दुर्घटना सहायता), हरित पत्र, केसरिया व शहरी पत्र (सस्ते खाद्यान्न), थालिया भाग्य, स्कूली बच्चों को मुफ्त पुस्तकें एवं वर्दियां, विधवा पेंशन, मातृत्व भत्ता आदि जैसी नई-नवेली योजनाओं ने कर्नाटक में एक बेहतर न्यायसंगत और समानतावादी समाज की स्थापना में योगदान दिया है। 1986-87 तक विभिन्न योजनाओं के लाभान्वितों का विवरण इस प्रकार है:-

योजनाएं	लाभान्वितों की संख्या
हरित पत्र (परिवार)	31,13,000
केसरिया व शहरी पत्र (")	49,97,000
मुफ्त पुस्तकें एवं वर्दियां	70,00,000
विधवा पेंशन	3,64,000
मातृत्व भत्ता	2,09,000

सरकार करती है, काम बोलता है

चाहे गांवों को पेय जल उपलब्ध कराना हो या निर्धन विधवाओं और गर्भवती महिलाओं को सहायता देनी हो, कर्नाटक का काम मिसाल पैदा करने वाला रहा है। उदाहरण के लिए 1983-87 के दौरान 56,000 कुएं खुदवाए गए हैं और 5,124 ग्रामों को पाइप से पानी की सुविधा दी गई है। आप यह जानकर हैरान होंगे कि आजादी के बाद के 35 वर्षों में कुल 47,726 कुएं खुदवाए गए थे।

ग्रामीण विद्युतीकरण की कहानी भी ऐसी ही शानदार है। सन् 1983 तक कुल 18,187 गांवों में बिजली पहुंचाई गई थी जबकि 1983-87 तक की 4 वर्ष की इतनी अल्प अवधि में और 7,251 ग्रामों में बिजली पहुंचाई गई है। और सुनिए, 1983 तक सिंचाई के लिए सिर्फ 3,59,494 पंप सेटों को बिजली दी गई थी जबकि 1983-87 की अवधि के दौरान 2,00,749 पंप सेटों को बिजली दी गई है। है न कमाल की बात!

तिलहनों के उत्पादन में राज्य का कार्य निष्पादन अद्वितीय रहा है। सिर्फ 1986-87 में ही 8.67 लाख टन उत्पादन हुआ जो देश में सबसे अधिक है।

किसान का बोझ कम और आसान

कर्नाटक ने कृषि क्षेत्र को जो छूट दी हैं, उनका भी कीर्तिमान है। सन् 1983 में सरकार ने सत्ता संभालते ही किसानों को करों में अनेक रियायतें दीं तथा उन्हें विशेष प्रोत्साहन भी दिए। उदाहरण के लिए **नाबार्ड** 15% की दर से ब्याज लेता है जबकि हमारी सहकारी समितियां किसानों को सिर्फ 7% ब्याज की दर पर ऋण देती हैं।

इतना ही नहीं!

सूखे के दौरान पशुओं की बेतहाशा बिक्री को रोकने के लिए छियासी गौशालाएं-सामुदायिक पशुशालाएं खोली गई हैं।

शुष्क भूमि नवीन विकास योजना से वर्षा के भरोसे रहने वाले 80% किसानों को लाभ होगा। हर जिले में 25,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई प्रबंध के अंतर्गत लाने की योजना है।

योजना आयोग ने आईआरडीपी को लागू करने में राज्य के प्रयासों की सराहना की है। इस कार्यक्रम से अब तक लगभग 6.79 लाख लोगों को लाभ पहुंचा है।

औद्योगिक नीति पहले ऐसी नहीं थी

सन् 1983 में घोषित "औद्योगिक नीति" से कर्नाटक के उद्योग जगत में एक क्रांति आई है। इस नीति का मुख्य लक्ष्य था- हर माह 1,000 लघु उद्योग स्थापित करना और वास्तव में इस लक्ष्य को पा भी लिया गया है। वर्ष 1984-85 के दौरान 11,606, वर्ष 1985-86 के दौरान 11,634 और वर्ष 1986-87 के दौरान 11,179 लघु उद्योग स्थापित किए गए।

गांधी जी का अनुकरण: सत्ता का विकेन्द्रीकरण

शायद कर्नाटक देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने गांधी जी के पंचायत राज के मधुर स्वप्न को साकार किया है। ग्राम स्तर तक सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने का एक क्रांतिकारी कदम। जनवरी 1987 में जिला परिषदों और मण्डल पंचायतों के लिए कराए गए सफल चुनावों से कर्नाटक के राजनैतिक इतिहास में एक नए अध्याय का शुभारंभ हुआ है। यह विकास कार्यों में लोगों की बढ़ी भागीदारी के स्वर्णकाल की पूर्व सूचना देता है। साथ ही राज्य के साधनों का ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बराबर वितरण भी स्तुत्य है।

प्राकृतिक विपदाएं हैं तो क्या है! ईमानदारी से जारी है बेहतर जीवन की खोज, हर घड़ी, हर रोज।

कर्नाटक सूचना

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

छाया लेख: रघु राय

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सुंदरवन नरभक्षी बाघ

पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी के किनारे सुंदरवन दुनिया का आखिरी झाड़ीदार (गरान) जंगल है. कलकत्ता से दक्षिण करीब तीन घंटे की कार यात्रा और फिर नौका यात्रा के बाद 4300 वर्ग किमी में फैले इस वन क्षेत्र तक पहुंचा जा सकता है. करीब तीन घंटे की नौका यात्रा के बाद सभ्यता का शायद अंतिम पड़ाव मिल जाता है— गोसाबा गांव. यहां का पूरा माहौल आज भी आधुनिक सभ्यता से अछूता जैसे पुरातन पवित्रता से सराबोर हो. जंगल में बीच-बीच में खाली जगह पर बसे हजारों गांव वाले मछली मारकर, लकड़ियां चुनकर और शहद इकट्ठा करके गुजर-बसर करते हैं. लेकिन जंगल भी उनसे अपनी कीमत वसूलता है. आज भी इस वन क्षेत्र में सैकड़ों नरभक्षी बाघ विचरण करते हैं और गाहे-ब-गाहे किसी-न-किसी व्यक्ति को अपना शिकार बना डालते हैं. पिछले 10 वर्षों में करीब 600 लोग इस तरह जीवन गंवा चुके हैं. आदमी और जानवर के इस सतत संघर्ष का सबसे त्रासद गवाह है विधवापाड़ा गांव जहां आज हर पांचवें घर में एक-न-एक विधवा है जिसका पति बाघों का शिकार बन गया. फीचर संपादक ***इंद्रजीत बधवार*** *की रिपोर्ट:*

पश्चिम बंगाल के वनाच्छादित मुहाने सुंदरवन को कई-कई द्वीपों में बांटने वाली कई-कई छोटी नदियों में एक है बिद्या. और इसी के किनारे पर बसा है आरामपुर गांव. सुंदरवन के वृक्षहीन इलाके का यह गांव मानो कालातीत रमणीयता की गोद में बसा है. गोबरपुती झोंपड़ियां सुबह-सुबह कोहरे को भेदती सूरज की किरणों से जैसे सुनहरी आभा से दीप्त हो उठती हैं. जनवरी की ठंड में भी वहां का रमणीय वातावरण कोयल की मधुर कूक, दूर नदी के कलकल स्वर

रॉयल बंगाल टाइगर के कहर से विधवाओं की संख्या में हुई वृद्धि के कारण आरामपुर का नाम बदल कर विधवापाड़ा कर दिया गया

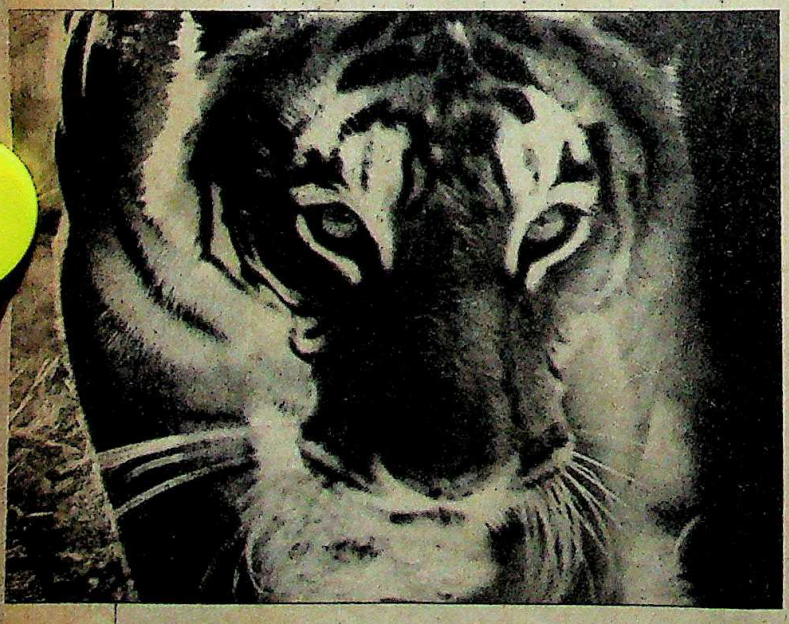

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

धोका बढ़ता कहर

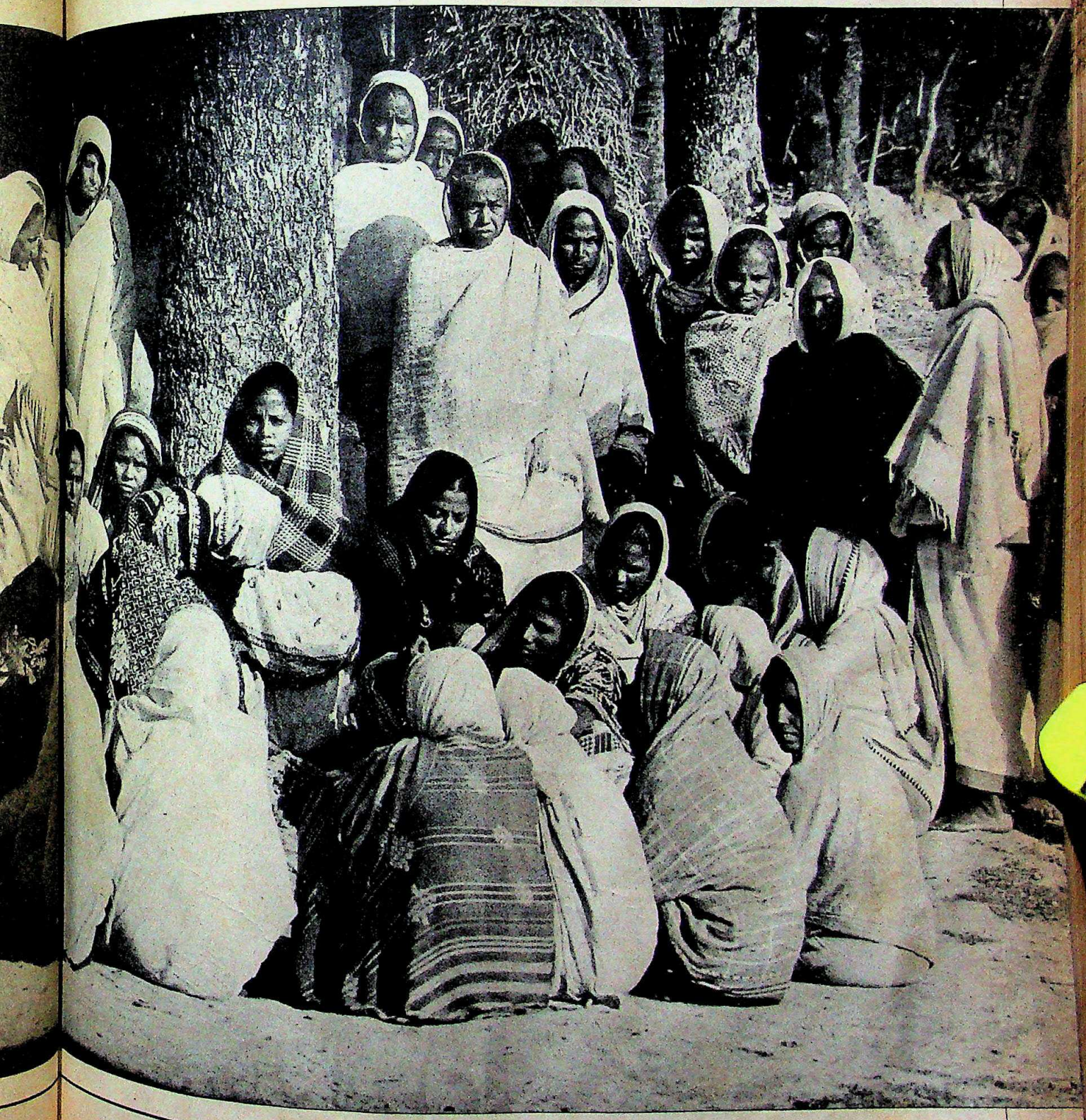

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

और कभी-कभार गुलिंदे की फरियादी चीख से गूंज उठता है.

नदी से उठा नम हवा का कोई आलसी झोंका गांव में केले, नारियल, खजूर, बबूल, माग्नोलिया और नीम के वृक्षों को जैसे सिहरा देता है. हर झोंपड़ी के पिछवाड़े पोखरों में चटकीले गुलाबी कमल हवा के झोंके से कांपते हैं मानो शैवाल भरे पोखरों की हरी सतह पर कोई छोटी नाव फिसल रही हो. झोंपड़ियों के आसपास बूढ़ों के खांसने की आवाजें, तो पिल्लों के साथ खेलते बच्चों की किलकारियां गूंजती रहती हैं. और घरों के भीतर औरतें चूल्हे-चक्की में व्यस्त.

गांव के इस पूरे परिदृश्य में एक कमी खटकती है. कोई पुरुष नहीं दिखता. करीब एक हफ्ते पहले एक सुबह वे आठ-आठ, बारह-बारह के जत्थों में इकट्ठे हुए और नौकाओं पर सवार होकर भेटकी, कुकरजीभी और बागदा चींगड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए रवाना हो गए. 250 मछुआरों के इस गांव का जीवन ऐसा ही रहा है. नदी में आठ-आठ घंटे नाव खेते हुए वे मछलियां पकड़ते हैं. दो दिन बाद वे घर लौटते हैं फिर से अपनी यात्रा शुरू करने के लिए. और महिलाएं अपने पतियों, बेटों की प्रतीक्षा करती रहती हैं.

दो बेटों और एक बेटी की मां रंजीता मलिक मछुआरों के जत्थे में गए अपने पति की दो हफ्ते से प्रतीक्षा कर रही है. हर सवेरे घर का काम निबटा कर वह कमर तक लंबे अपने बालों को खोलती है और पड़ोस के पोखरे में नहाने चली जाती है. नहाने के बाद वह वन बीबी के छोटे मंदिर में पूजा करने चल देती है. वन बीबी सुंदरवन के मछुआरों और वनवासियों की कुलदेवी मानी जाती हैं. कहा जाता है कि वन में जानवरों से वे उनकी रक्षा करती हैं. वन बीबी को नारियल और फूल चढ़ाकर रंजीता बाघ से अपने पति की रक्षा की भीख मांगती है. बाघों ने उसकी कई सखियों को विधवा बना दिया है.

अकेले आरामपुर के ही आसपास जवान और बूढ़ी विधवाओं की संख्या करीब 60 है जिनके पतियों को सुंदरवन के रॉयल बंगाल टाइगर खा गए. करीब एक दशक पहले गांव वालों ने इस गांव का नाम आरामपुर से बदलकर विधवापाड़ा रख दिया था.

विधवापाड़ा की अभागिनों की सूची में सबसे नया नाम 50 वर्षीया निर्मला मंडल का है. उसकी चार बेटियां और दो बेटे हैं. 13 महीने पहले मछली पकड़ने के एक अभियान के दौरान एक बाघ ने उसके पति सुखीचरण पर हमला कर दिया और उसकी हत्या कर दी. गांव लौटने पर सुखीचरण के साथ गए एक लड़के ने उसे बताया कि उसके पति को बाघ उठा ले गया. निर्मला बताती है, "मेरे बेटे भी अच्छे मछुआरे बन रहे थे लेकिन अब मैं उन्हें जंगल में नहीं जाने देती." निर्मला अब पड़ोस के घरों का चौका-चूल्हा करके किसी तरह जीवन निर्वाह करती है.

साठ वर्षीया सरला मलिक ने यह सब इतना देखा और भोगा है कि नई विधवाओं की दुखद कथा और उनकी दुर्दशा पहले से उनकी

मछुआरे सिर के पीछे मुखौटा लगा लेते हैं ताकि अक्सर पीछे से हमला करने वाले बाघ धोखा खा जाएं

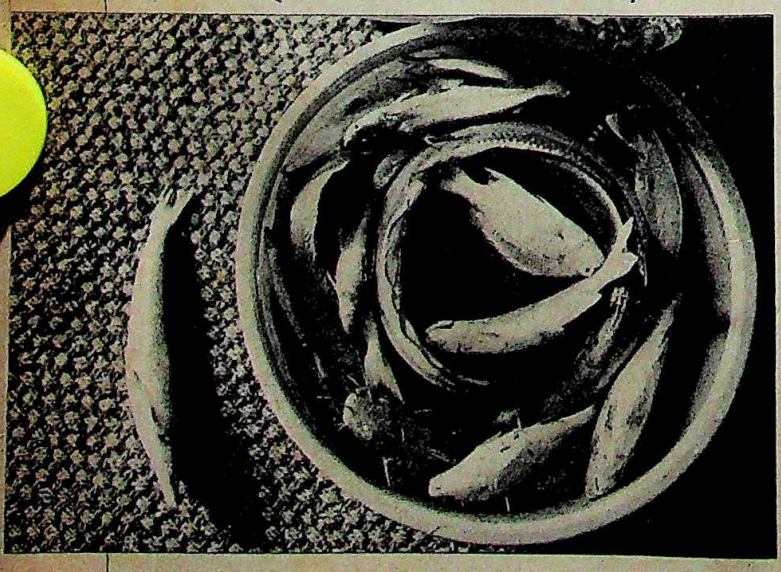

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जानी-समझी है. उसके पति की मृत्यु एक दशक पहले हो गई थी. वह कहती है, "मुझे तब की पूरी याद है. मेरा बेटा गोपाल भी सात लोगों के जत्थे में उनके साथ था. एक नाव में तीन आदमी होते थे. पीरखाली से एक दिन की यात्रा के बाद वे हमेशा लौट आते थे. वे अपने साथ एक मटका ताजा पानी ले जाते थे क्योंकि नदी का पानी खारा है. उनकी नावों पर दस दिन तक के भोजन के लिए चावल रहता था. वे नाव पर ही पकाते-खाते और उसी में सो जाते. जब मेरे पति की मृत्यु हुई तब मेरा बेटा गोपाल उनके बगल में ही खड़ा था. लेकिन वह कुछ नहीं कर सका. जब बाघ दहाड़ मारकर उन पर टूट पड़ा था तब वे सभी अपना होश-हवास खो बैठे थे. लेकिन जब बाघ उन्हें खींच कर ले जा रहा था तब भी मेरे पति बचाओ, बचाओ की गुहार लगा रहे थे. यह देखकर गोपाल चीखने-चिल्लाने लगा. उसे किसी तरह खींचकर नाव पर रखा गया."

वह बताती है, "उस दिन सवेरे मैं पड़ोस में अपनी बेटी के घर गई और उससे मैंने बताया कि इस बार किसी अमंगल की आशंका मुझे हो रही है." वह और उसकी बेटी लौटती नावों को गांव से थोड़ी दूर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पर एक सुरक्षित टीले से देखती रहतीं. वह बताती है कि एकाएक उसे आभास हुआ कि उसके पति वाला जत्था धीरे-धीरे उसकी तरफ चला आ रहा है. लेकिन उसके पति जत्थे में नहीं थे.

अब परिवार के निर्वाह के लिए गोपाल मछली मारने जाया करता है. मुआवजे के रूप में सरला को अब तक सिर्फ 600 रुपए का कर्ज मिला है, बगल के कस्बे और थाना गोसाबा की स्टेट बैंक शाखा से, वह भी हाल ही में. इन रुपयों से उसने चार बकरियां खरीदीं. चारों बकरियां पेचिश के कारण तुरंत ही मर गईं. अब बैंक ने कर्ज अदायगी के लिए सरला पर कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है.

विधवापाड़ा गोसाबा थाने के करीब 300 गांवों में से एक है. सुंदरवन के 1500 वर्ग किलोमीटर के संरक्षित वन क्षेत्र में से करीब 375 वर्ग किलोमीटर का इलाका आबादी वाला है. इस इलाके के दूसरे गांवों जैसे दयापुर, अमलामेथी, आइनपुर, लाहिड़ीपुर के भी लोग सुंदरवन के बाघों के शिकार हुए हैं. पर विधवापाड़ा इन सबसे अलग क्यों है इस बारे में पंचायत समिति के उपाध्यक्ष सूरजकांत राय कहते हैं, "दूसरे गांवों में तो लोग धान की खेती तथा बकरी पालन भी करते हैं. लेकिन इस गांव के सभी परिवार मछली मारने पर ही निर्भर हैं." इस गांव के हर पुरुष को 300 रुपए की मासिक आय के लिए इन छोटी नदियों में मछली मारने के लिए साल में दस महीने जंगल में बिताने का खतरा मोल लेना पड़ता है.

40 वर्षीया द्रौपदी मंडल के पति राजेश्वर को 18 महीने पहले एक बाघ उठा ले गया था. वह बताती है, "रात-दिन मैं अपने पति को जंगल में जाने से मना करती रहती थी. मैं उनसे कहा करती थी कोई दूसरा धंधा कर लें लेकिन हमेशा उनका जवाब होता था हम क्या खाएंगे, हमारे तीन बच्चे क्या खाएंगे. तभी एक दोपहर लौटे जत्थे में से वे गायब थे. मेरा बेटा भी पति के साथ जाया करता था लेकिन अब मैं उसे नहीं जाने देती. हम दूसरे घरों में काम करके जीवन चलाते हैं. बेटा मर गया तो हम तो मर ही जाएंगे."

दो साल पहले बाघ के शिकार हुए परिवारों को 2,000 रुपए का मुआवजा दिया गया. लेकिन बाघों के हमले में वृद्धि के कारण गांववासियों द्वारा हाल ही में वन अधिकारियों के घेराव और आंदोलन के कारण मुआवजे की राशि 5,000 रुपए तक बढ़ा दी गई. मुआवजा केंद्र सरकार की परियोजना 'प्रोजेक्ट टाइगर' की तरफ से दिया जाता है. और वह भी परियोजना अधिकारियों, पुलिस और पंचायत समिति की मिली-जुली तहकीकात के बाद.

देश के अभयारण्यों में बाघों की वर्तमान संख्या करीब 4000 है. इनमें से सुंदरवन के 2,600 वर्ग किलोमीटर के संरक्षित इलाके में 260 बाघों के होने का अनुमान है. सुंदरवन का कुल क्षेत्रफल 4,262

मेघनाथ (नीचे) उन भाग्यशाली लोगों में है जो बाघ के चंगुल से बच गया शायद देवी वन बीबी की कृपा से

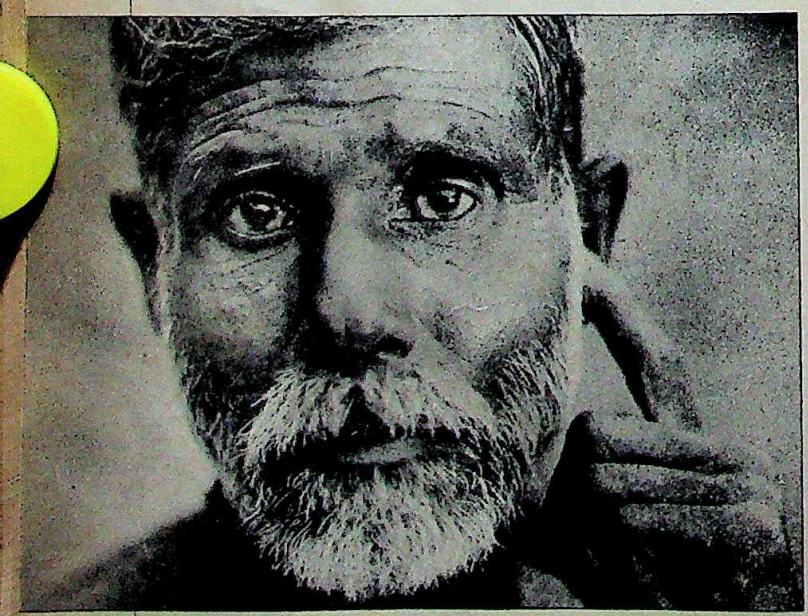

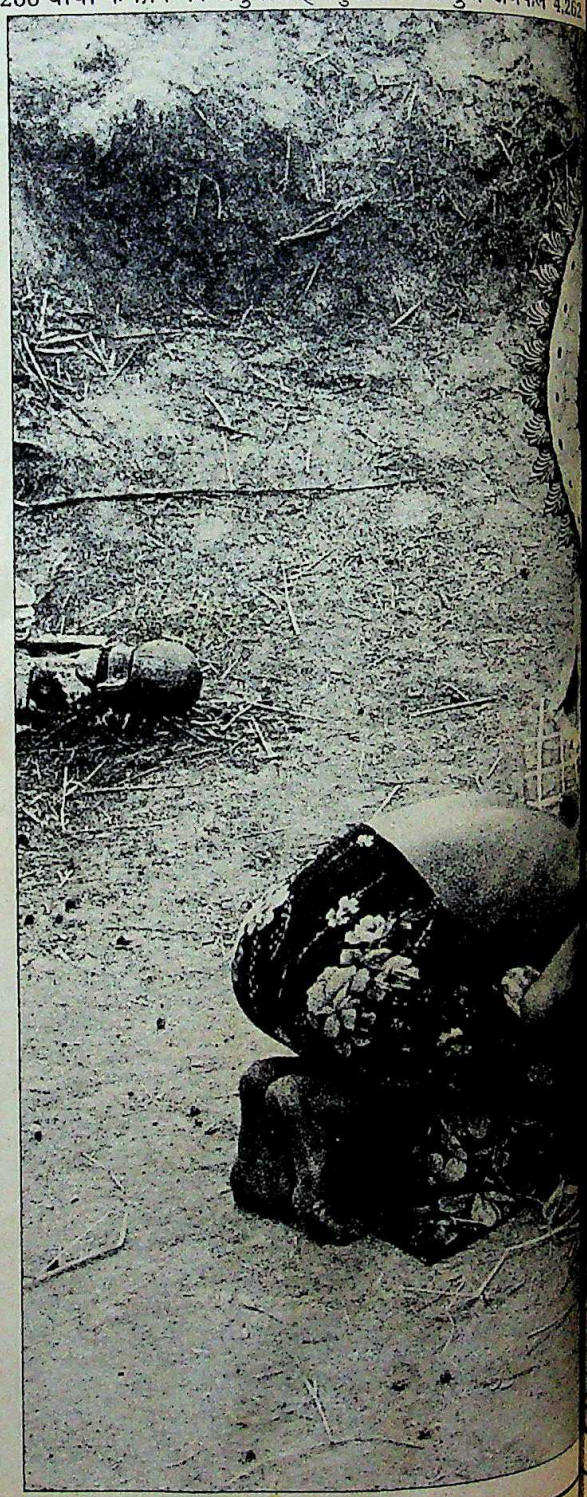

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वर्ग किलोमीटर है. बाघों की गिनती उनके पंजों के छाप से होती है. आदमी की उंगलियों के छाप की तरह ही बाघों के पंजों के छाप कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलते.

इस वन में अक्सर जाने वाले स्थानीय अधिकारियों और गांववासियों के अनुसार बाघों की आबादी बढ़ रही है. जंगल में बिना फारेस्टमेंस के घुसने और शिकार करने पर पाबंदी 1974 में लगाई गई थी इसके पहले इस इलाके में 19 बाघों को मारने वाले गोसाबा के 70 वर्षीय अनिल नाथ का अनुमान है कि इस वन में बाघों की संख्या 400 से भी ऊपर पहुंच गई है. नाथ कहते हैं, "पिछले पांच सालों में बांग्लादेश में बाघों के अनधिकृत शिकार में बेहिसाब बढ़ोतरी के कारण वहां से सुंदरवन में बाघ काफी तादाद में आए हैं. और जिस इलाके से ये बाघ आए हैं वहां के सभी बाघ नरभक्षी हैं."

सरकारी अनुमान के अनुसार इस इलाके में हर वर्ष 25-30 लोग बाघों के शिकार होते हैं. लेकिन स्थानीय वन अधिकारियों के गैर-सरकारी अनुमान के अनुसार यह संख्या 50 के करीब है. एक अधिकारी ने कहा, "चूंकि वन में मछली मारने और लकड़ी काटने

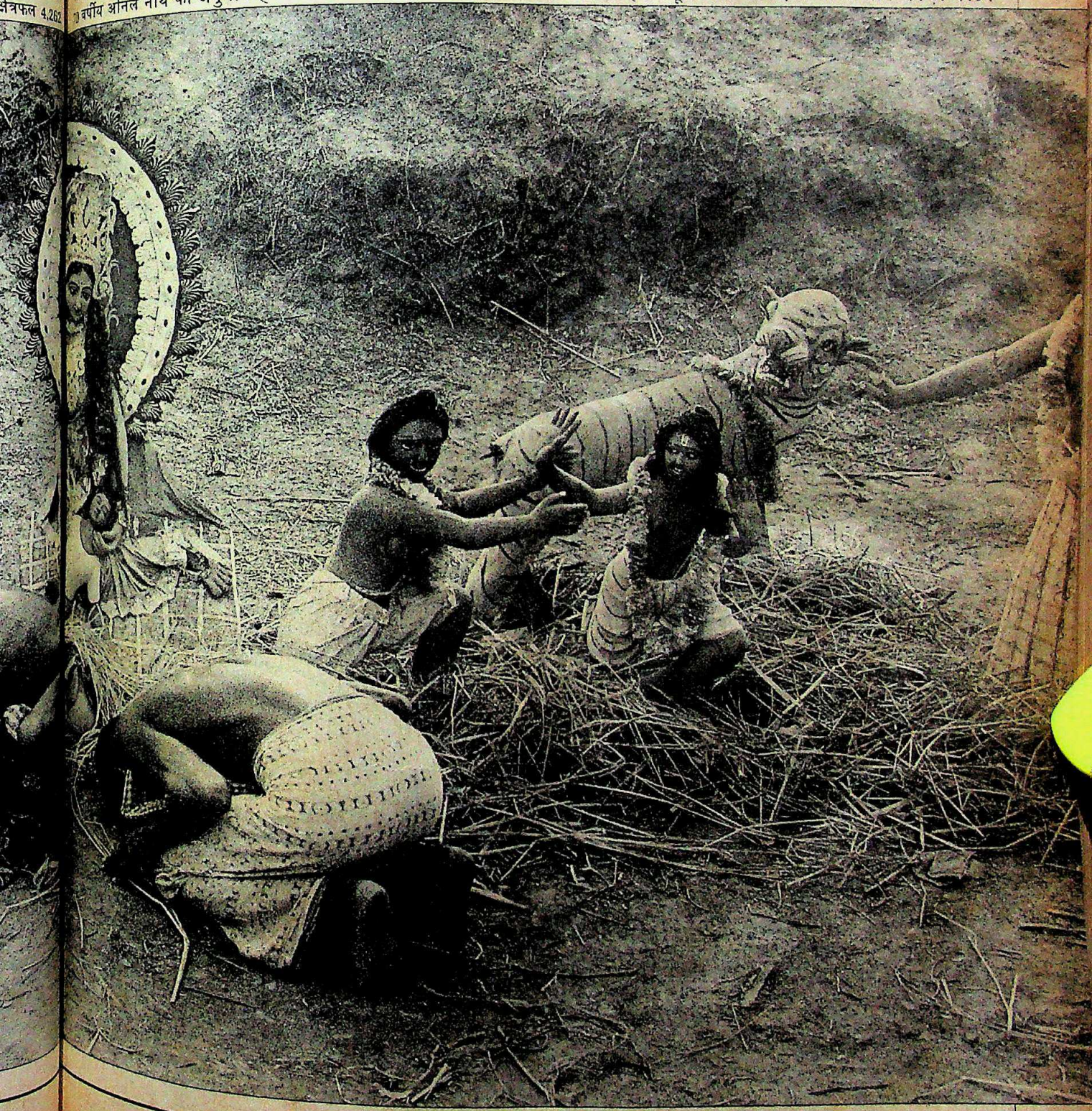

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जाने वाले अधिकांश लोगों के पास लाइसेंस नहीं होता है इसलिए ज्यादातर मामले दर्ज नही कराए जाते. अगर इन लोगों में से कोई मारा भी जाता है तो उसके परिवार को मुआवजा नही मिलेगा, उलटे जांच-पड़ताल में भी फंसना पड़ेगा.''

अपनी जीविका के लिए जंगल में जाने को मजबूर मछुआरों, शहद इकट्ठा करने वालों और लकड़हारों पर बाघों के हमले कम करने के लिए 'प्रोजेक्ट टाइगर' के तहत कई प्रयोग हो रहे हैं. ज्यादातर वन प्रखंडों में सशस्त्र सुरक्षा कर्मचारी नियुक्त हैं. उन्हें आदेश है कि जंगल में गांववासियों की पहुंच वाले इलाकों में बाघ के आने का अंदेशा होते ही वह अपनी बंदूक से हवाई फायर करें. इसके साथ ही वन अधिकारियों को स्थानीय गांववासियों जैसा दिखने वाला बैटरी चालित पुतला जगह-जगह लगाने का निर्देश दिया गया है. इन पुतलों पर पुराने कपड़े लपेट दिए जाते हैं ताकि इनमें मनुष्य शरीर की गंध आ जाए. इसके पीछे सोच यह है कि अगर बाघ इन पर हमला करे तो उसे बिजली के जबरदस्त झटके लगें. ये झटके ज्यादा घातक नहीं होंगे. शहद इकट्ठा करने का मौसम अप्रैल से शुरू होकर तीन महीने तक चलता है. इस दौरान भारी संख्या में लोग शहद इकट्ठा करने इन जंगलों में जाते हैं. इसी दौरान 40 ऐसे पुतले चुनिंदा जगहों पर लगाए गए और फसलों के इर्दगिर्द बालू बिखेर दिए गए.

सजनखाली के थाना प्रभारी जी.पी. सेन के अनुसार इस इलाके में दो बाघों ने इन पुतलों पर हमला किया और बिजली के झटके उन्हें लगे. इसका पता चश्मदीदों से नहीं बल्कि वहां की जमीन पर पाए गए निशानों से मिला. बालू पर बाघ के पंजों के छाप देखे गए. निशान से यह भी पता चलता है कि बिजली के झटके लग जाने के बाद बाघ जमीन पर लोटपोट हो गया होगा.

सुरक्षा का दूसरा उपाय वन में जाने वालों के सिर के पीछे मुखौटा लगाने का है. सेन बताते हैं, ''सुंदरवन के बाघों का एक विचित्र चरित्र है. वन में घनी घास और बाघों के शरीर के रंग के कारण उन्हें देख पाना कठिन होता है. और ये बाघ हमेशा पीछे से हमला करते हैं. इसलिए अगर कोई आदमी सिर के पीछे मुखौटा पहन लेता है तो यह संभावना है कि बाघ यह समझे कि आदमी उसे देख रहा है और इस तरह वह शायद हमला करने का इरादा छोड़ दे.''

आम तौर पर बाघ का हमला तेजी से, अचूक और बस कुछ सेकेंडों का मामला होता है. बाघ अपने शिकार को मुंह में दबोचकर उठा ले जाता है, और बाकी लोग दहशत से बस देखते ही रह जाते हैं. ज्यादातर हमले दोपहर बाद या शाम के वक्त ही होते हैं. मछुआरों पर बाघ आम तौर पर नदी में भाटे के समय तब हमला करता है जब वे नदी के किनारे-किनारे जाल बिछाने के लिए जगह ढूंढते फिरते हैं या फिर वह तब हमला करता है जब वे खालियों (छोटी नहरों) में कमर तक पानी में उतरकर अपना जाल बिछाते हैं.

'प्रोजेक्ट टाइगर' के निदेशक आर.एल. सिंह कहते हैं, ''बाघों को

बाघ को देखते ही जंगल के गार्ड हवाई फायर करते हैं, बाघों को चकमा देने के लिए बैटरी चालित पुतले लगाए जाते हैं

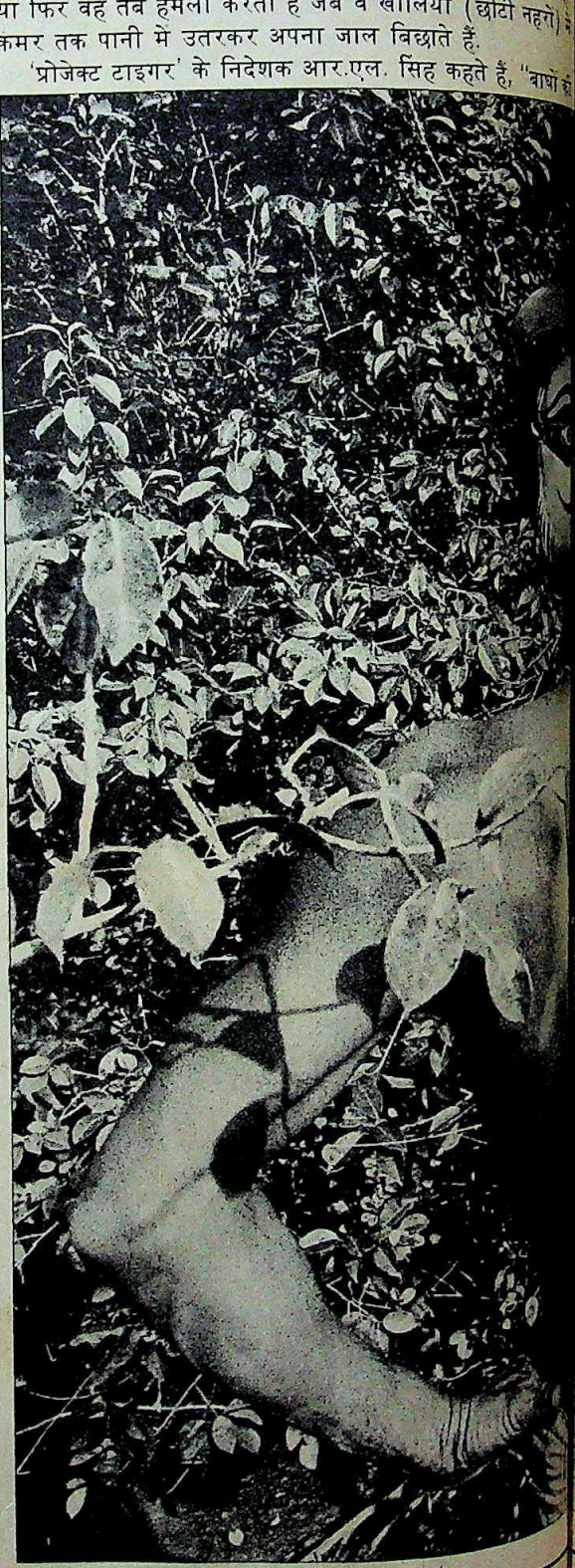

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बरकरार रखने के लिए हमें एक अमूल्य सबक मिल गया है. बाघ बहुत अनुशासित प्राणी है. वह अगर अपने संरक्षित क्षेत्र से बाहर किसी गांव में चला जाता है तब वह आदमी को नहीं मारता. लेकिन अपने इलाके में वह हिरन और आदमी में फर्क नहीं करता."

अनिल नाथ का कहना है कि कई बार तो बाघ किसी मछुआरे परिवार का दो-दो दिन तक पीछा करता है और धीरे-धीरे उनके नजदीक आता जाता है. दहाड़ मारकर हमला करने के पहले वह पूरे होश के साथ इंतजार करता है ताकि हमला खाली न जाने पाए. नाथ कहते हैं, "आम तौर पर वह अपने शिकार पर बहुत पहले से ही नजर रखता है. और दूसरे लोगों के नजदीक होने के बावजूद वह उसी व्यक्ति पर हमला करता है जिसको उसने लक्ष्य किया होता है."

इस इलाके में बाघ के सबसे ताजा शिकार बने माकपा के पंचायत सदस्य मंसूर गाजी. वे पिछले दिसंबर में चामता प्रखंड में सात सदस्यों के दल के साथ शहद का सर्वेक्षण करने गए थे तभी उन पर कहर टूट पड़ा. बाघ ने उन पर दूर से सीधा निशाना लगाया जबकि दूसरे लोग उससे हाथ भर ही दूर थे. नाथ बताते हैं कि जंगल में आवाज दूर-दूर

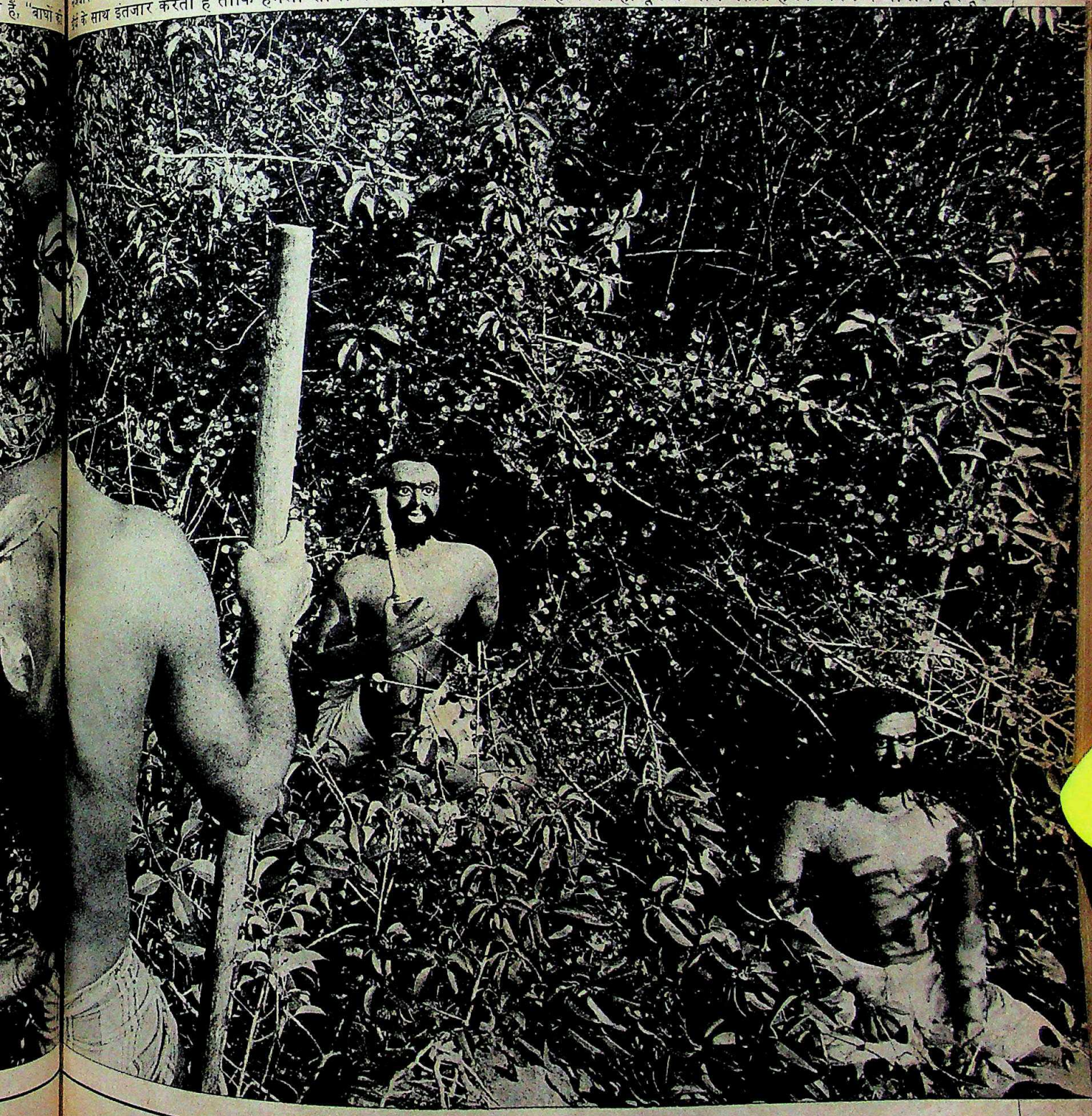

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तक सुनाई पड़ती है. गाजी अपनी नाव की छप्पर की मरम्मत के लिए लकड़ी जुटाने जंगल में गए थे. उनका दल नाव पर पड़ाव डाले हुए था. "बाघ ने जरूर लकड़ी काटने की आवाज सुन ली होगी और गाजी की तरफ धीरे से बढ़ आया होगा. इसके बाद से वह उनके इंतजार में रहा होगा." लकड़ी काटने के बाद गाजी अपनी नाव पर लौट आए थे और फिर दो घंटे बाद पांच लोगों के साथ जंगल में दूसरे काम से गए. जैसे ही वे किनारे पर आए, बाघ ने उन पर पीछे से हमला किया और उनकी गरदन जबड़े में दबाकर चूर कर दी.

कहावत और आंकड़े दोनों ही यही बताते हैं कि बाघ के हमले के बाद क्या बीतती है यह बताने के लिए कोई बचा नहीं रहता. जो बच जाते हैं वे खुद ही कहावत बन जाते हैं. ऐसे ही एक व्यक्ति हैं अमलामेथी के 72 वर्षीय मेघनाथ. उनकी गरदन के बाएं और कान पर पड़े निशान चार साल पहले नेता धूप में उन पर हुए बाघ के हमले की गवाही देते हैं. वहां वे 12 लोगों के एक दल के अगुआ बनकर गए थे जिसमें उनके भाई जितेंद्र नाथ भी थे. घटना 3 बजे शाम के थोड़ी देर बाद ही हुई. मेघनाथ और उनके भाई भाटे के समय नदी की घनी झाड़ियों वाले किनारे पर अपने जाल के एक छोर को बांधने गए थे.

वे याद करते हैं, "बाघ एकाएक दहाड़ मारकर कूद पड़ा. मेरा भाई उसके हमले की ठीक सीध में था पर उसके कंधों पर झटका देते हुए वह सीधे मुझ पर लपका. मैं जमीन पर गिर गया. मैं अपने ऊपर उसकी सांस को महसूस कर रहा था. मैं सांस रोके पड़ा रहा और मन ही मन एक मंत्र का जाप करने लगा. मैं उसकी गरदन पकड़कर उसका मुंह अपने से दूर करने की कोशिश कर रहा था, हालांकि मुझे पता चल गया था वह अपने दांत भिड़ा चुका है क्योंकि गरदन और चेहरे से खून के रिसने का अंदाज मुझे हो रहा था. बाकी लोग चीख-चिल्ला करके बाघ को डराने की कोशिश कर रहे थे. इसी बीच जितेंद्र बाघ को पीछे से पकड़कर अपने पूरे जोर से पीछे खींचने की कोशिश करने लगा." जितेंद्र बताते हैं, "मैं बाघ के कान और गरदन को नोंचकर उसे भरपूर चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा था. वह अपने पंजे से मेरे भाई को दूर खींच ले जाने की कोशिश कर रहा था. लेकिन यह सब पांच सेकेंड से ज्यादा नहीं चला होगा. एकाएक वह उन्हें छोड़कर जंगल में भाग गया."

नदी में भाटे के दौरान मछुआरे मछली पकड़ने के लिए नदी में नावों को एक कतार में खड़ी कर देते हैं खतरे से खेलते हुए

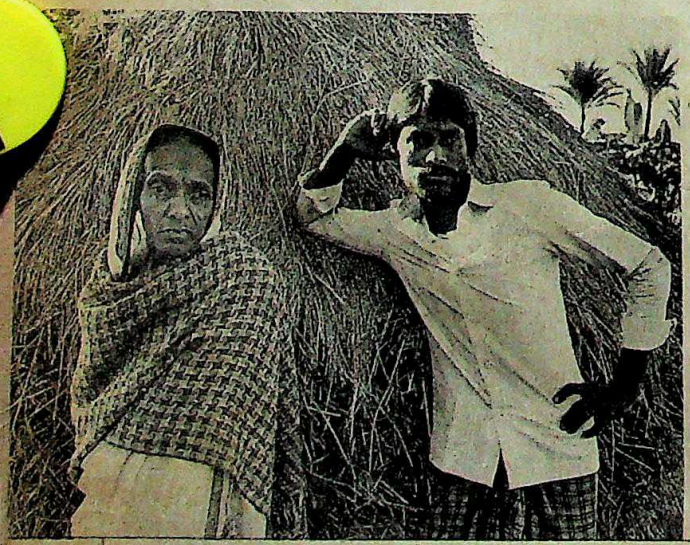

सैकड़ों मछुआरे छोटे-छोटे जत्थों में नौकाएं लेकर बिहा नदी के पीरखाली इलाके में भाटा आते ही चल देते हैं क्योंकि तभी नदी में ज्यादा मछली मिलने की संभावना होती है. शाम घिरते ही वे अपनी छोटी रंग-बिरंगी नौकाओं को एक जगह ले आते हैं. लगता है कैसे कोई जंगी बेडा खड़ा हो गया हो. मछुआरे आग जलाकर घनी झाड़ियों वाले किनारों पर कमर तक पानी में उतरकर जाल समेटने लगते हैं. थोड़ी देर बाद सब कुछ ठहर जाता है. नदी पर बहती नौकाओं का गांव मानो ध्यान की मुद्रा में चला गया हो.

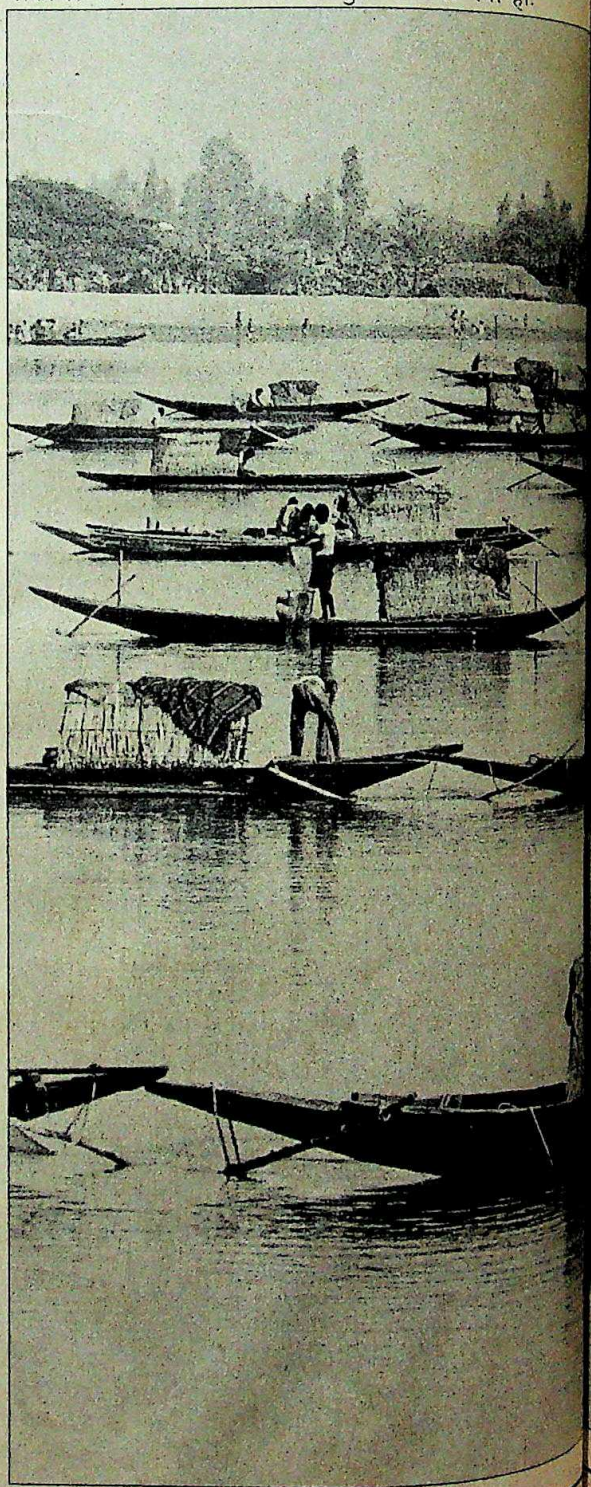

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बाघ के प्रति गांववासियों का नजरिया दोहरा है. जब वह दिख जाए तो उसे मारना वे जरूरी मानते हैं. लेकिन फिर भी उसे जानी दुश्मन नहीं मानते. नजरिये का यह दोहरापन वनरक्षक देवी वन बीबी के मिथक के रूप में भी प्रकट होता है. इस मिथक के अनुसार दक्खिन राय सुंदरवन के बाघ देवता हैं जो अपनी इच्छा के अनुसार आदमी से बाघ बन जाते हैं. कहा जाता है कि एक बार बाघ के रूप में दक्खिन राय ने शहद इकट्ठा करने गए दल पर हमला किया और एक विधवा के बेटे दुखी को उठा ले गए. गांववालों ने वन बीबी से प्रार्थना की. वन बीबी ने दुखी को बाघ से बचाकर अपने कब्जे में तो ले लिया. लेकिन दक्खिन राय ने जंगल के देवता बरखंड गाजी से मामले का फैसला करने को कहा. गाजी ने फैसला सुनाया कि दुखी को एक घड़ियाल पर बिठाकर उसकी मां के पास भेज दिया जाए और यह भी निर्देश दिया कि वनवासियों तथा बाघों को एक दूसरे के क्षेत्र का सम्मान करना चाहिए.

इस दंतकथा के जन्म के शायद हजारों वर्षों बाद आज भी मनुष्य और खूंखार जानवर के बीच संघर्ष जैसे अनवरत जारी है.

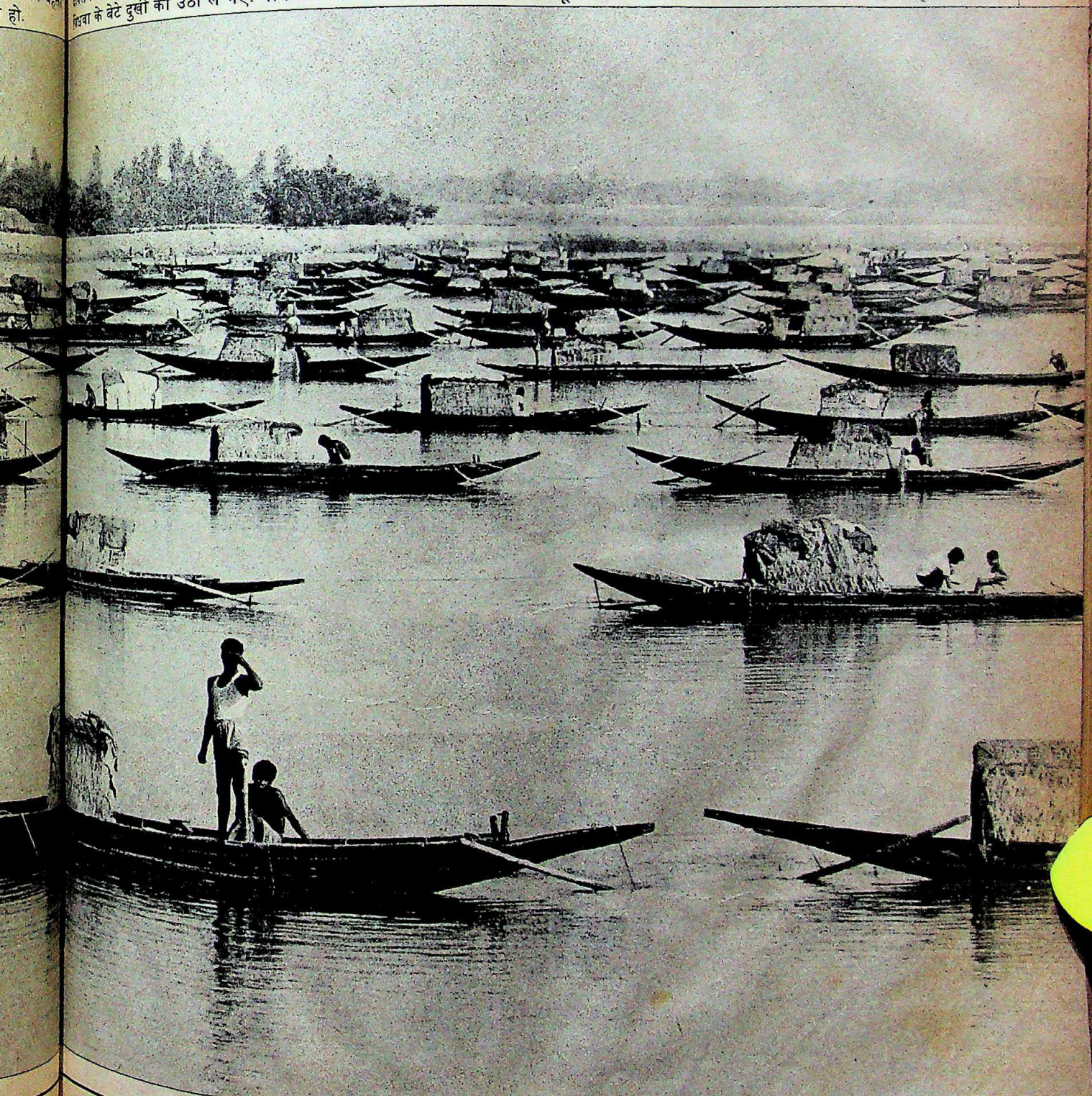

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बाल रोग

सुविधाओं का अकाल

देश की चिकित्सा सेवाओं में बच्चों की घनघोर उपेक्षा

उत्तरी दिल्ली के हिंदूराव अस्पताल का वार्ड नंबर 12. बच्चों के इस वार्ड के एक छोटे से केबिन में एक-दूसरे से सटे हुए आठ बिस्तर लगे हैं जिन पर अलग-अलग उम्र के 14 मरीज बच्चे एक-दूसरे में गड्डमड्ड हुए दिखते हैं. एक बिस्तर के एक कोने में दो महीने की बच्ची संतोष लेटी हुई है. पास खडे हुए उसके पिता मुकेश बच्ची का हाथ थामते हुए बताते हैं कि संतोष को तीन दिन पहले निमोनिया के इलाज के लिए वहां भर्ती कराया गया था.

. 10 वर्षीय संदीप को दौरे पड़ने की वजह से अस्पताल में भर्ती किया गया है. पिछले तीन दिनों के दौरान संतोष के बिस्तर पर इलाज के लिए भर्ती किया जाने वाला वह तीसरा बच्चा है. ये दोनों बच्चे उन गिनेचुने भाग्यशाली भारतीय बच्चों में से हैं जिन्हें संकट के समय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं. एक स्थानीय डॉक्टर के अनुसार यदि संतोष दिल्ली से बाहर रहने वाला बच्चा होती तो उसके बचने की आशा न के बराबर थी क्योंकि दिल्ली से 100 किमी दूर तक वैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं जो उसे इस अस्पताल में मिलीं.

प्रभात पंजियार

सरकारी आंकड़े बताते हैं कि भारत में पैदा होने वाले 50 प्रतिशत बच्चे अपना पांचवां जन्मदिन मनाने से पहले ही मर जाते हैं और राष्ट्रीय मृत्युदर में बच्चों का योगदान बराबर का होता है. जो बच जाते हैं उनमें से 40 लाख बच्चे हर साल कुपोषण और उचित स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण विकलांग हो जाते हैं. इनमें से 30 लाख तो मानसिक रूप से विकृत और 2.5 लाख आंखों से हाथ धो बैठते हैं. मरने वालों में से 5 लाख बच्चे तो ऐसे होते हैं जिन्हें डायरिया के इलाज के लिए न तो डिस्पेंसरी से 50 पैसे कीमत वाला ग्लुकोज-नमक मिश्रण मिल पाता है और न अस्पताल की सुविधा. इसी तरह समय पर प्रतिरोधी टीकों के न मिल पाने के कारण 2 लाख बच्चे खसरे से पीड़ित होकर मर जाते हैं.

मगर इसके बावजूद हालत यह है कि देश में न तो उचित संख्या में बाल रोग विशेषज्ञ तैयार हो रहे हैं और न उचित अनुपात में बच्चों के लिए चिकित्सा सेवाएं ही उपलब्ध हैं. भारत के लगभग 110 मेडिकल कॉलेजों में से हर साल लगभग 13 हजार डॉक्टर तैयार होकर निकलते हैं. लेकिन जनसंख्या में बच्चों का अनुपात 40 फीसदी होने के बावजूद इन डॉक्टरों में से केवल 550 ही बाल रोग विशेषज्ञ होते हैं. और बाल रोग नर्सों की संख्या तो न के बराबर है. राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार प्रति 10 हजार बच्चों के लिए एक विशेषज्ञ के हिसाब से भारत में आज 32 हजार विशेषज्ञों की जरूरत है. सन 2000 तक 40 हजार डाक्टरों की जरूरत होगी. पर इनकी वास्तविक संख्या आज केवल 4000 ही है. सन 2000 में यह संख्या 11,150 ही हो पाने की उम्मीद है. औद्योगिक देशों में 800 बच्चों पर एक डॉक्टर का अनुपात रहता है.

एक बिस्तर पर दो बाल रोगी: 'भाग्यशाली' होने की सुविधा

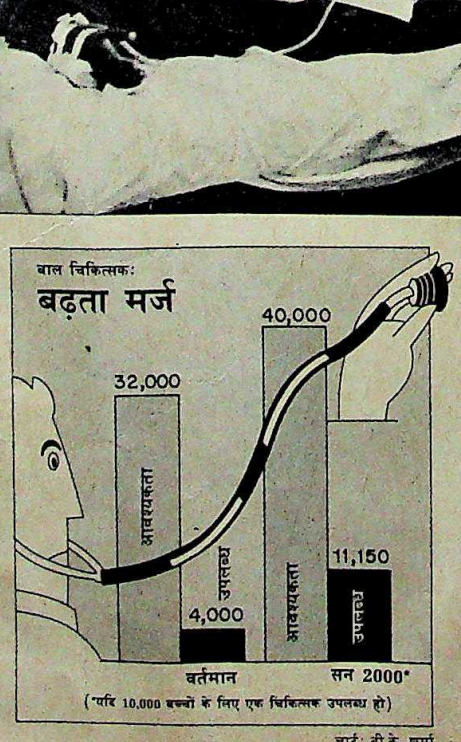

चार्ट: बी.के. शर्मा

पिछले दिनों भारतीय बाल रोग विशेषज्ञों के संगठन आईएपी के वार्षिक अधिवेशन में चौंकने वाली एक बात सामने आई कि भारतीय मेडिकल कॉलेजों में से हर एमबीबीएस डॉक्टर के 5 वर्षीय प्रशिक्षण के दौरान बाल रोगों के बारे में केवल 15 घंटे पढ़ाया जाता है जबकि अंतरराष्ट्रीय बाल रोग कांग्रेस के अनुसार विकासशील देशों में बाल रोग शिक्षा का हिस्सा कम-से-कम 100 घंटे अवश्य होना चाहिए. कुल चिकित्सा प्रशिक्षण का केवल 60वां हिस्सा ही बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित होता है.

पढ़ाई के अलावा एमबीबीएस परीक्षा की हालत तो और भी खराब है. तीन कॉलेजों को छोड़ शेष सभी कॉलेजों में अंतिम

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

डायरिया का इलाज

चले ढाई कोस

विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े बताते हैं कि तीसरी दुनिया के देशों के लगभग 50 लाख बच्चे हर साल डायरिया की वजह से असमय मौत के शिकार हो जाते हैं. इनमें से लगभग 15 लाख भाग्यहीन बच्चे भारत के होते हैं. पतले दस्त और उल्टियों के कारण शरीर से पानी और लवणों का एक बड़ा हिस्सा बह जाता है और निर्जलीकरण हो जाता है. यदि कुछ ही घंटों के भीतर पानी और नमक की पूर्ति न की जाए तो रोगी का मरना लगभग तय रहता है.

1960 में कलकत्ता और ढाका में किए गए वैज्ञानिक अध्ययनों से पहली बार पता चला कि यदि हैजे के रोगी को ग्लुकोज और नमक का घोल पिलाया जाए तो शरीर इस घोल के पानी और नमक को आसानी से सोख लेता है और निर्जलीकरण का खतरा कम हो जाता है. ओरल हाईड्रेशन थैरपी (ओआरटी) के नाम से विख्यात इस इलाज को विज्ञान पत्रिका 'लैसेट' ने 1987 में इसे बीसवीं सदी की सबसे महान मेडिकल खोज की उपाधि दी.

इस दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनीसेफ जैसे संगठनों ने तीसरी दुनिया की इस महामारी पर नियंत्रण पाने के लिए ओआरटी के प्रचार और प्रसार का एक विशाल अभियान खड़ा कर दिया है. इस पर बीमारी के सबसे बड़े शिकार भारत में ओआरटी का प्रसार अभी भी सरकारी लालफीताशाही के चंगुल में फंसकर कछुए की चाल चल रहा है. डायरिया के कारण हर रोज 4 हजार बच्चों की मृत्यु के बावजूद केवल छठी योजना के दौरान ही डायरिया नियंत्रण कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया गया और सातवीं योजना में कहीं जाकर ओआरटी प्रणाली को मातृ-शिशु कल्याण कार्यक्रम का हिस्सा बनाया गया. हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 25 करोड़ रुपए की लागत से ओआरटी प्रशिक्षण और ग्लुकोज-नमक मिश्रण के वितरण का 'राष्ट्रीय अभियान' छेड़ने और इस बीमारी से 'युद्धस्तर' पर निपटने का एलान कर दिया है पर ये सारे प्रयास अभी भी फाइलों की शोभा बने हुए हैं.

निर्माण भवन के एयरकंडीशंड कमरों से इस कार्यक्रम का संचालन करने वाले एक सरकारी प्रवक्ता का दावा है कि देश में ओआरटी के प्रशिक्षण और प्रचार का विशाल अभियान चलाया जा रहा है तथा अक्तूबर से सभी सरकारी डिस्पेंसरियों और अस्पतालों में ओआरटी के पैकेट रखना और मरीजों को देना जरूरी कर दिया गया है. लेकिन राजधानी के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के बाल रोग विभाग के डॉक्टर बताते हैं कि केवल एक डॉक्टर ने ही आज तक ओआरटी पैकेट के दर्शन किए हैं. दिल्ली के लगभग सभी अस्पतालों में ओआरटी तैयार करने और बांटने का काम लगभग पहले दिन से ही

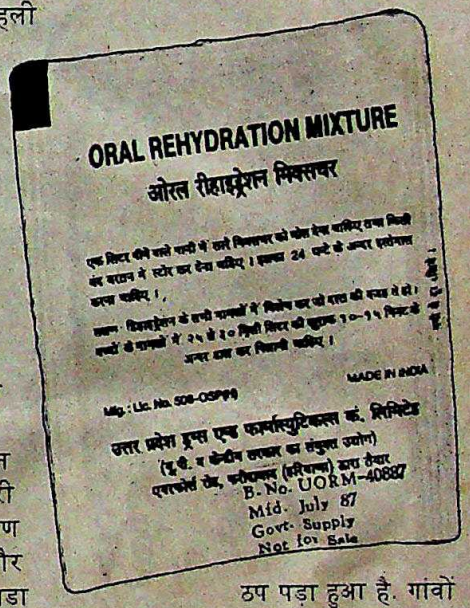

ठप पड़ा हुआ है. गांवों में भी हालत खस्ता ही है.

विश्व स्वास्थ्य संगठन के फार्मूले के अनुसार एक लिटर घोल बनाने के लिए 3.5 ग्राम खाने का नमक, 2.5 ग्राम खाने का सोडा, 1.5 ग्राम पोटाशियम क्लोराइड और 20 ग्राम ग्लुकोज या 40 ग्राम चीनी की जरूरत होती है. इसकी कुल बाजार लागत 50 पैसे से भी कम बैठती है. लेकिन बड़ी-बड़ी दवा कंपनियां एक लिटर घोल बनाने वाले मिश्रण के लिए 5-6 रुपए से लेकर 30 रुपए तक वसूल कर रही हैं. पर स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है, "ओआरटी को गांव के पनवाड़ी और परचूनिए तक पहुंचाने के लिए सरकार जल्दी ही यह फैसला करने जा रही है."

—विजय क्रान्ति

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पुरानी फिल्में

दूसरी पारी में भी जमीं

छठे और सातवें दशक की हिंदी फिल्में एक बार फिर चल निकलीं

सिनेमाघरों पर 'हाउस फुल' के बोर्ड, टिकट खिड़की पर लंबी कतारें और टिकट ब्लैक करने वालों का धुआंधार धंधा. भीतर घुसने के दरवाजे पर अब ऐसे दर्जनों लोग खड़े देखे जा सकते हैं जो देर से आने वाले दर्शकों से फालतू टिकट प्राप्त करने की होड़ में रहते हैं. कुल मिलाकर वातावरण ठीक ऐसा होता है मानो दर्शकों की मनपसद फिल्म लंबे इंतजार के बाद दिखाई जाने वाली हो. तो क्या अमिताभ बच्चन की कोई धूमधड़ाके वाली फिल्म रिलीज हो रही है? क्या यह विनोद खन्ना और डिम्पल कपाडिया का एक नया शगूफा है? या फिर गोविंदा और फरहा के ठुमकते कूल्हों की नई किश्त पेश की जा रही है?

जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा. आज देश के 7,669 सिनेमाघरों के सामने दर्शकों की भीड़ संकट से घिरी हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री से रिलीज होने वाली नई फिल्में देखने के लिए नहीं बल्कि बीते जमाने की उन फिल्मों को देखने के लिए उमड़ रही है, जिनमें राजकपूर की 'संगम' की तरह रोमांस अधिक था और हिंसा कम. यहां तक कि रमेश सिप्पी की 'शोले' जैसी वे फिल्में भी फिर से लोकप्रिय हो रही हैं.

पिछले साल बंबई की हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री ने उससे पहले साल के मुकाबले 10 फीसदी कम, यानी 127 फिल्में रिलीज कीं. फिल्म निर्माताओं के लिए इससे भी अधिक तकलीफ भरी बात यह रही कि इनमें से केवल एक चौथाई फिल्में ही अपना खर्च वापस वसूल पाईं. इसके अलावा 1986 में राजकपूर की 'राम तेरी गंगा मैली' के बाद अब तक एक भी फिल्म हिट नहीं हो पाई है जो फाइनांसरों को खुश कर सके.

उल्टे हुआ यह कि पिछले छह महीनों में 60 और 70 वाले दशकों की फिल्मों ने एक बार फिर टिकट खिड़की पर हंगामा मचाना शुरू कर दिया है. राजश्री पिक्चर्स के प्रधान ताराचंद बड़जात्या का अनुमान है कि इन दिनों लगभग उतनी ही पुरानी फिल्में चल रही हैं जितनी नई फिल्में 1987 के दौरान रिलीज हुई थीं. वे बताते हैं, "आजकल तो वे फिल्में भी हिट हो रही हैं जो अपने जमाने में बुरी तरह पिट गई थी."

एक प्रमुख निर्माता गुलशन राय का कहना है कि पुरानी फिल्मों में से लगभग 90 फीसदी फिल्में अच्छा धंधा कर रही हैं जबकि नई फिल्मों में से केवल 10 फीसदी ही. फिल्मी दुनिया के कई अनुभवी लोगों की मान्यता है कि पुरानी फिल्मों की इस अचानक लोकप्रियता से यही सिद्ध होता है कि दर्शक नई फिल्मों के हिंसा और सेक्स के मसाले से तंग आ चुके हैं.

अपनी एक के बाद एक सफल फिल्म के कारण 70 वाले दशक में 'सिलवर जुबली स्टार' का खिताब पाने वाले राजेंद्र कुमार भी इस बात से सहमत हैं. वे कहते हैं, "पुराने दिनों में फिल्मों की कहानी, संगीत और अभिनय हर चीज बेहतर थी. आजकल की फिल्में तो केवल धूमधड़ाम भर हैं." वे बताते हैं कि इन दिनों उनकी कम से कम एक दर्जन पुरानी फिल्में सिनेमाघरों में चल रही हैं.

उस काल की एक प्रसिद्ध तारिका नूतन बताती हैं, "ज्यादातर नौजवानों के लिए फिल्में अनजाने इतिहास के समान हैं, जिसके बारे में वे अपने पुरखों से सुनते आए हैं."

पुरानी फिल्मों की एक बड़ी ताकत उनका संगीत है. शंकर-जयकिशन और मदन मोहन जैसे संगीत-निर्देशकों के काल के दौरान बनी पुरानी फिल्मों में कालजयी गीत-संगीत की भरमार है. यह बात ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया ने भी पुरानी फिल्मी गीतों के कैसेट जारी करने पर पाई है. फिल्मफेयर के संपादक रऊफ अहमद कहते हैं, "अमस्त ज्यादातर नौजवान इन मधुर गीतों के कारण भूत होकर पुरानी फिल्मों को देखते हैं." निर्माता मोहन कुमार की फिल्म 'आप की बहार आई' फिर से हिट हो रही है.

फिल्म निर्माता आत्माराम कहते हैं, "पुराने समय में फिल्मों के निर्माण में एक बारीकी का ध्यान रखा जाता था. लेकिन पिछले 15 सालों से फिल्मों में हिंसा को महिमामंडित करने के सिवाय कुछ नहीं किया जा रहा." निर्माता मोहन सहगल की फिल्म 'वह मैं नहीं' अपने बाद में जब दुबारा प्रदर्शित की गई तब उसे देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी. यह देखकर वहां के वितरक फिल्म-उद्योग की पत्रिका में विज्ञापन दे निर्माता के प्रति अपनी ज्ञता जाहिर की. महेंद्र पारिख बताते हैं कि पहले फिल्म की कहानी पर ध्यान दिया जाता था. अब हीरोइन या खलनायक के चरित्र को बुरा दिखाने में ही पूरा ध्यान लगाया जाता है.

हाउस फुल भीड़ खींचती राजकपूर की फिल्म 'संगम': सदाबहार आकर्षण

फिल्म पत्रिका 'ट्रेड गाईड' के अनुसार पिछले साल 'प्रतिघात' एकमात्र फिल्म जिसका व्यवसाय 'ट्रिपल-ए' श्रेणी में आ सका. इस साल दूसरी सफल फिल्म 'जंगल का कानून' थी. इन दोनों ही फिल्मों में क्रूरतम हिंसा का प्रदर्शन किया गया. लेकिन व्यावसायिक हिंदी सिनेमा में हिंसा की वस्तु का दिवालियापन इस कदर बढ़ गया कि उपरोक्त फिल्मों को राजनैतिक फिल्म का दर्जा मिल गया.

फिल्मों में लगातार खलनायक के अभिनय के लिए मशहूर एक अभिनेता प्रेम चोपड़ा पूर्वानुमानित दृश्यों को ठूंसने से हिंदी फिल्मों को हुए नुकसान को स्वीकार करते हैं. उनकी तरफ लगता है कि दर्शक अब ऐसे दृश्यों

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

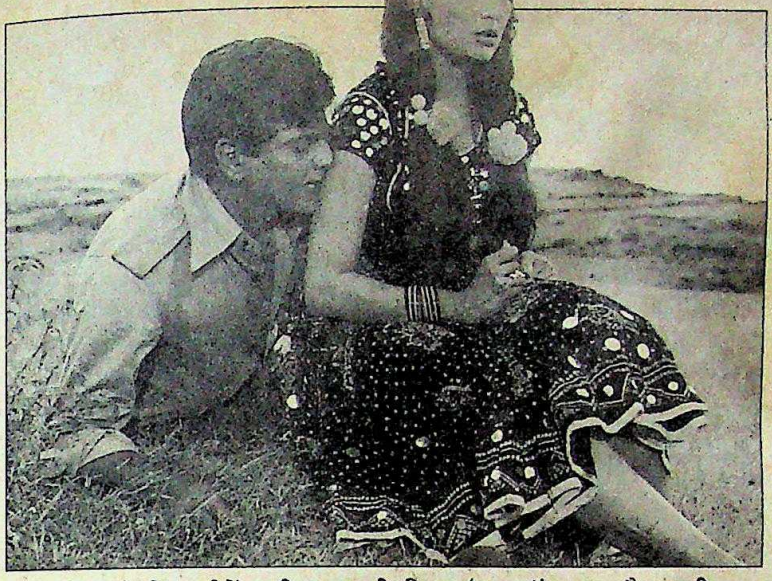

आशा पारिख-जीतेंद्र की शुरुआती फिल्म 'कारवां': एक और पारी

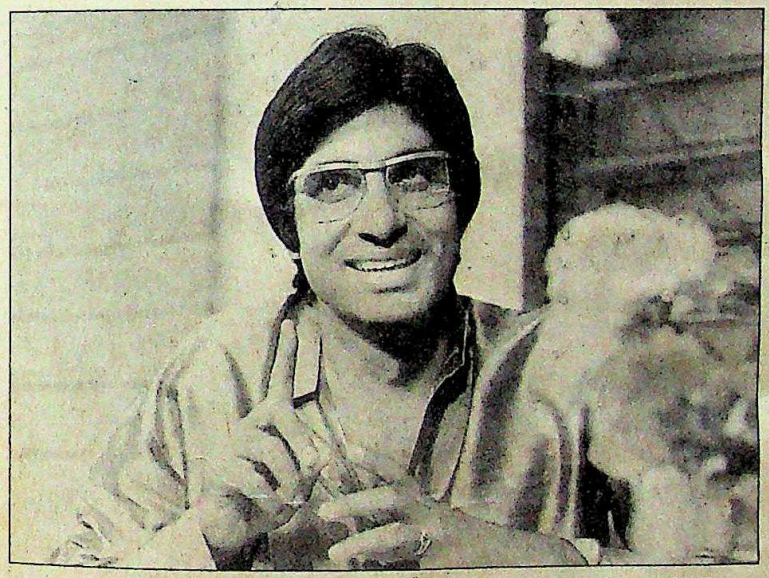

अमिताभ बच्चन की शुरुआती फिल्में भी आजकल खूब चल रही हैं

पुराने गीतों का आकर्षण 'आप आए बहार आई' के चलने से प्रमाणित

और सिर्फ 180 करोड़ रुपए ही निर्माताओं को मिले, बाकी पैसा वितरकों और सिनेमाघर वालों की थैली में गया. पिछले साल निर्माताओं द्वारा लगाई गई पूंजी 250 करोड़ रुपए थी.

फिल्मों के निर्माण में आने वाले खर्चों में वृद्धि और कुछ ही अभिनेताओं द्वारा 30 से 40 फिल्मों को हाथ में लेने से फिल्म निर्माण क्षेत्र में बिखराव की स्थिति आई और हालात अधिक खस्ता हो गए.

ऐसी हालत में ऋषिकेश मुखर्जी जैसे प्रतिष्ठित फिल्म निर्माताओं को भी इस स्थिति से छुटकारा पाने का रास्ता नहीं सूझ रहा है. उल्लेखनीय है कि विमल राय और महबूब जैसे निर्देशकों की हिंदी फिल्मों की परंपरा को बनाए रखने का श्रेय उन्हीं को जाता है. मुखर्जी कहते हैं, "भविष्य अंधकारमय है और अच्छे फिल्म निर्माताओं के हाथ में कोई फिल्म नहीं है. मैं तो संन्यास लेने पर विचार कर रहा हूं."

फिलहाल तो जहां एक ओर देश के सिनेमाघरों में शीशा टूटने की आवाज, गाड़ियों की अंधाधुंध भागमभाग और दनादन गोलियां बरसाने वाले दृश्यों की फिल्मों से भले ही आधी-अधूरी भीड़ जुटा पा रही है पर वहीं दूसरी ओर शांत और मधुर संगीत प्रधान पुरानी फंतासी फिल्मों के प्रदर्शन में खचाखच भरे सिनेमाघरों को देखकर फिल्मी दुनिया के लोगों को कुछ आशा बंधी है. अगर पुरानी फिल्मों की पुनर्प्रतिष्ठा एक और युग के पूरा होने का संकेत है तो हिंदी फिल्मों के कुछ बेहतर भविष्य की कल्पना की जा सकती है.

—एम. रहमान

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रथाथिन रथामे

परदे पर नया प्रयोग

दक्षिणी भाषाओं में अब हिंदी फिल्में रूपांतरित होने लगेंगी

अब जल्दी ही तुगभद्रा उल्टी बहने लगेगी. दक्षिण भारतीय फिल्मों का हिंदी में रूपांतरण तो आम बात है. पर यदि मद्रास के एवीएम स्टुडियो में चल रहा महत्वपूर्ण परीक्षण सफल रहा तो हिंदी फिल्में दक्षिणी भाषाओं में भी ढाली जाने लगेंगी.

बाक्स आफिस पर हिट हिंदी फिल्म 'मिस्टर इंडिया' बालाजी फिल्मस् के बैनर तले तमिल में रूपांतरित की जा रही है. आश्वस्त दिखते प्रोड्यूसर के. बालाजी जिन्होंने चार लाख रुपए में इस फिल्म के अधिकार खरीदे हैं, कहते हैं, "मुझे इस प्रयोग के सफल रहने में कोई शंका नहीं है. यह न सिर्फ आम लोगों को आकर्षित करने वाला विषय है, बल्कि फिल्म में शामिल जादुई मसाला या सच कहा जाए तो आम दक्षिण भारतीय तत्व यहां के दर्शकों का मन जरूर मोह लेंगे."

श्रीदेवी के स्थान पर हिंदी फिल्मों की ही एक नायिका मीनाक्षी शेषाद्रि इस फिल्म के जरिये पहली बार तमिल परदे पर उतरेंगी. उनके साथ प्रसिद्ध अभिनेता भाग्यराज मिस्टर नट्टू की भूमिका निभाएंगे. वे मूल 'मिस्टर इंडिया' के हीरो अनिल कपूर का स्थान लेंगे. फिल्म का निर्देशन बालाजी प्रोडक्शन के जाने-माने निर्देशक के. विजयन कर रहे हैं. उनके निर्देशन में यह 57वीं फिल्म होगी. पटकथा खुद भाग्यराज ने लिखी है, जिसमें 40 दिन के विचार-विमर्श के बाद उन्होंने कई तब्दीलियां की हैं. मजे की बात है कि इस तमिल रूपांतरण का नाम 'रथाथिन रथामे' (खून के रिश्ते) रखा गया है. ये दो शब्द अक्सर दिवंगत एमजीआर अपनी आम सभाओं में लोगों को सबोधित करते समय इस्तेमाल किया करते थे. फिल्म के नाम को उचित ठहराते हुए भाग्यराज मानते हैं, "हां, मैं चाहता हूं कि जब भी और जहां भी फिल्म दिखाई जाए, दर्शक एमजीआर को याद करें." भाग्यराज मानते हैं कि इस फिल्म में राजनीति का समावेश भी है, "एमजीआर भी अपनी फिल्मों में यह तरीका अपनाते थे और मैं भी ऐसा ही कर रहा हूं. बहरहाल, विषय स्वयं देशभक्तिपूर्ण हावभाव वाला है." निर्देशक विजयन भी इस बात से सहमत हैं, "प्रत्येक व्यक्ति खासकर दर्शक जानता है कि भाग्यराज की फिल्में अधिकतर दो अर्थों वाली होती हैं और अमूमन उनमें अश्लील संकेत होते हैं. लेकिन इस फिल्म से उन्होंने राजनैतिक संदेशों की ओर रुख किया है." अपनी राजनैतिक महत्वाकांक्षाओं को स्वीकार करते हुए भाग्यराज कहते हैं, "मैं राजनीति में उस समय शामिल हुआ था जब एमजीआर बीमार पड़े थे. लेकिन राज्य में हो रही मौजूदा राजनैतिक घटनाओं ने मुझे चुप रहने पर मजबूर कर दिया. अगले दो साल तक मेरी यही स्थिति रहेगी."

बालाजी: आश्वस्त

एक करोड़ के भारी-भरकम बजट वाली 'रथाथिन रथामे' के दो शूटिंग शेड्यूल पूरे हो गए हैं और इस साल अगस्त में इसके रिलीज होने की उम्मीद है. भाग्यराज ने लीक से हटकर खुद एक ऑटो-चालक की भूमिका निभाई है. उनकी पहचान माथे पर बंधी एक रंगीन पट्टी से होती है जबकि मूल फिल्म में अनिल कपूर ने तड़क-भड़क वाली पोशाक पहन रखी थी. भाग्यराज की फिल्म में, जैसी कि उम्मीद की जाती है, खलनायक को ज्यादा कुछ करने को नहीं है. मूल फिल्म में सर्वव्यापी मोगांबो के रूप में खलनायक अमरीश पुरी की जगह मलयालम अभिनेता कैप्टन राज ने ली है.

भाग्यराज कहते हैं, "मेरी फिल्मों में अमूमन खलनायक नहीं होता लेकिन इसमें कैप्टन राज की छोटी सी भूमिका रहेगी." वे कहते हैं, "इसकी जगह मैं बच्चों की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करना पसंद करूंगा जो फायदेमंद साबित हो." भाग्यराज ने मूल फिल्म वीडियो पर देखी है. वे उत्साह से बताते हैं, "मिस्टर इंडिया दक्षिण भारतीय दर्शकों के लिए असीम और उत्तेजक संभावनाएं प्रस्तुत करती हैं."

'रथाथिन रथामे' के एक दृश्य में मीनाक्षी और भाग्यराज: खूब जमेगी जोड़ी

अपने रीमेक की खूबियां गिनाते हुए भाग्यराज मीनाक्षी शेषाद्रि की भूमिका का ब्यौरा भी देते हैं, "तमिल रूपांतरण में मीनाक्षी की भूमिका मूल फिल्म से कोई ज्यादा भिन्न नहीं है. मुझे यकीन है कि वह यह भूमिका बखूबी निभा लेगी. हालांकि यह भी सच है कि मूल फिल्म में श्रीदेवी ने उत्कृष्ट अदाकारी की है."

मूल फिल्म की भारी सफलता और इसमें दक्षिण भारतीय तत्वों की भरमार को देखते हुए भाग्यराज की यह फिल्म हिट ही साबित हो सकती है.

—ललिता दिलीप

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सही आकार, रहे एकसार सालों साल, साल दर साल

साल दर साल, साल दर साल, साल दर साल,

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

संक्रांति और सनातनता
दर्शन
डॉ. छगन मोहता
वागदेवी प्रकाशन, बीकानेर (राज.)
कीमत: 40 रु., पृ. 108

दर्शन

ज्ञान परंपरा की दृष्टि

डॉ. छगन मोहता के भाषणों का यह संपादित संग्रह उनके चिंतन के आधारों की झलक देता है. वे भारतीय समाज को उसकी अपनी ज्ञान परंपरा के आधार पर देखते हैं. वे स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय थे और साथ ही सामाजिक-सांस्कृतिक आंदोलनों में. पिछले वर्ष उनका देहावसान हुआ. कहते हैं कि यज्ञ की प्रक्रिया ब्रह्मांड की प्रक्रिया है. इसके पीछे बलिदान का नियम है. यज्ञमय जीवन वह है जिसमें आजीविका भी सम्यक हो, साथ ही वाणी, व्यवहार, विचार और दृष्टि भी सम्यक हो. इस आधार पर सम्यक स्मृति और सम्यक ध्यान से सम्यक समाधि संभव होती है. वैसी स्थिति में ही अनायास नैतिकता होती है. सायास नैतिकता तो नैतिकता नहीं है. व्यवहार कुशलता है, चतुराई है.

डॉ मोहता कहते हैं कि जो समाज इन आधारों वाला नहीं होता, वहां शोषण ही सामाजिक आधार होता है. शोषण वहां है, जहां स्वयं को साध्य और दूसरों को अपना साधन माना जाता है. ऐसी स्थिति में विभव-तृष्णा और काम-तृष्णा अमर्यादित रूप में बढ़ती रहती है. इस तृष्णा का मूल कारण अज्ञान है, अविद्या है.

इस मनीषी ने समग्रता पर बल दिया है. वे कहते हैं कि समग्रता यह है कि वस्तु के आंतरिक एवं बाह्य— उभय पक्ष जाने जाएं. आंतरिक पक्ष मूल है, बाह्य उसका विस्तार.

वे यह भी कहते हैं कि जितने भी विभाजन हैं, वे नाम रूप के हैं. उनसे परे चिदाकाश है. चिदाकाश नित्य मुक्त है. उसके लक्षण हैं सत-चित एवं आनंद. आनंद सुख नहीं है, वह सुख-दुख से परे की बोध-स्थिति है. यह चिदाकाश मूल्यों का भंडार है. ये मूल्य शाश्वत हैं. व्यक्ति-चित्त में विविध संस्कार, वासनाएं एवं संकल्प होते हैं, जो चिदाकाश की चिन्मयता का बोध नहीं होने देते, अहंकार का आवरण डाले रहते हैं. किंतु इस अहंकार से परे एक सार्वभौम अद्वितीयता हर व्यक्ति में प्रतिबिंबित होती है. इसीलिए हर व्यक्ति एक ही अद्वैत सत्ता का अंश है और साथ ही हर व्यक्ति अद्वितीय है. अद्वैत और अद्वितीयता— ये दो डॉ. मोहता के चिंतन के आधार पद हैं. इसी आधार पर वे कहते हैं कि राज्य ऐसा हो, जिसमें व्यक्ति की अद्वितीयता की सर्जनात्मक अभिव्यक्ति हो सके और होती रह सके. इसीलिए राज्य को विकेंद्रित होना चाहिए.

डॉ. मोहता कहते हैं, "जितना केंद्रीकरण होगा, उतनी ही नौकरशाही हावी होगी. नौकरशाही एक अजीब-सी नस्ल है. मशीन और मनुष्य के समागम से एक प्राणी पैदा हुआ है, जो नौकरशाह है... उसमें संवेदनशीलता और मूल्य नाम की कोई चीज नहीं होती." नौकरशाह के प्रति ऐसे व्यंग्य वस्तुतः 'डिसेंट' (असहमति) की यूरोपीय परंपरा का अंग है. 'डिसेंट' अंततः सदा व्यवस्था को ही सुदृढ़ करती है. नौकरशाहों आदि को ऐसे व्यंग्य कसकर मध्यवर्गीय लोग हल्के हो लेते हैं. एक अमूर्त क्रोध हवा में तैरता भटकता रहता है. सत्य यह है कि नौकरशाह मशीन नहीं होते, क्षुद्र एवं समाज विरोधी होते हैं. किंतु आधुनिक यूरोपीय 'स्टेट' की तो अवधारणा ही समाज के विरुद्ध एवं समाज को समाप्त करने वाली है. 'स्टेट' के अधीन नागरिकों की भीड़ होती है, जिन्हें वह नियंत्रित करता रहता है— भेड़ों की तरह. इस प्रकार अद्वितीय जीवंत व्यक्तियों को समाप्त का विशिष्ट सदस्य नहीं, अमूर्त 'मासेज' घोषित कर देना राज्यकर्ता वर्ग द्वारा समाज के विरुद्ध युद्ध जारी रखना है.

इस प्रकार के शासक वर्गीय लोग, जिनमें नौकरशाह मुख्य होते हैं, मशीन नहीं होते. अपने निकृष्ट, आपराधिक एवं पापमय स्वार्थों के प्रति वे अतिसंवेदनशील, अति चौकन्ने, बेहद होशियार होते हैं. आपराधिक प्रशासन, असामाजिक योजनाएं, वृहद् समाज का स्वत्व-हरण, फिर उसके उद्धार की उदात्त घोषणाओं का पाखंड— ये ही उनके मूल्य होते हैं. उन्हें मशीन कहना उनकी अनजाने सेवा करना है. ऐसे अमूर्त क्रोध समाज में सिर्फ निरर्थक भटकाव, थकान, हताशा और हार का ही कारण बनते रहते हैं.

कहीं-कहीं ऐसे घालमेलों के बावजूद ये भाषण एक मेधावी चिंतक के विचारों का संग्रह है. पूरी पुस्तक में अत्यंत महत्वपूर्ण सूक्त एवं [illegible] फैले हुए हैं.

—[illegible]

राइन के किनारे
संस्मरण
आलोक मेहता
प्रकाशक: पराग प्रकाशन, दिल्ली-32
कीमत: 25 रुपए, पृष्ठ 112

संस्मरण

पश्चिमी जर्मनी के नजदीक

"... क्या कहा? बच्चा होने वाला है नाइन-नाइन (नहीं-नहीं) यह तो मुनासिब है. बच्चे की आवाज से हमारी नींद [illegible] होगी. लिहाजा आप कहीं और [illegible] मकान तलाशिए."

"सचमुच यह एक पहेली है कि [illegible] और शारीरिक सौंदर्य के इस प्रदर्शन [illegible] यहां के लोगों की रुचि कम क्यों [illegible] होती? हर रात वही बोतल और [illegible] प्रदर्शन-लड़कपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापा—लेकिन [illegible] इसकी ललक कम होती नहीं दिखाई देती."

"... बुढ़ापा आने के बाद तो सामान्य जर्मन स्त्री-पुरुष आए [illegible] कब्रिस्तान के चक्कर लगा-लगाकर वह स्थान देखते रहते हैं [illegible] उनका शरीर दफनाया जाएगा..."

"निश्चित रूप से यह जर्मनों की जिंदादिली का प्रमाण ही है [illegible] उन्होंने अनथक परिश्रम और साहस से केवल पच्चीस-तीस वर्षों में [illegible] हुए खंडहरों के साथ तहस-नहस हो चुकी अर्थव्यवस्था को नए सिरे [illegible] सजा-संवारकर खड़ा कर दिया..."

"जर्मन टेलीविजन पर... एक बार कलकत्ता के जनजीवन पर [illegible] दिखाई गई तो यहां तक कह दिया गया कि एक ही बस्ती के एक [illegible] के घर में पानी बिजली दी जाती है लेकिन उससे जुड़े मुस्लिम के [illegible] में नल से पानी नहीं आता...."

ये टिप्पणियां पश्चिम जर्मनी की उस तस्वीर के टुकड़े हैं [illegible] पत्रकार आलोक मेहता ने 'राइन के किनारे' बैठकर बहुत नजदीक [illegible] देखा. रेडियो 'डायट्शे वैले' (वायस आफ जर्मनी) में तीन [illegible] नौकरी के दौरान मिलने वाले अनुभव की छाप पुस्तक पर [illegible] दिखाई देती है. और यहीं से यह पुस्तक उन विवरणों से अलग [illegible] जाती है जो दो-चार दिन की जर्मन यात्रा पर गए कुछ पत्रकार [illegible] लेखकों ने लेखमालाओं के रूप में पत्रिकाओं में लिखे हैं.

लेखक की कलम जर्मन समाज की अच्छाइयों और कमजोरि[illegible]

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विभाजन रेखा को पहचानते हुए कहीं उस समाज की तारीफ करती है तो अगली ही सांस में उसकी खामियों पर चुटकी भी लेती है. पुस्तक में जर्मन रीति-रिवाजों से लेकर त्यौहारों, थिएटर प्रेम, साहित्य, विवर प्रेम तथा इतिहास, पुलिस, भारत-जर्मन संबंधों और प्रेस जैसे कई विषयों को छुआ गया है. इसी विविधता का परिणाम है कि किसी अध्याय में तो एकदम निजी और अंतरंग अनुभवों का चुटीला वर्णन है और कहीं एकदम डाक्यूमेंटेशन शैली उभरती है.

कई स्थानों पर जर्मन शब्दों के उच्चारण में भारी गलतियां हैं. उदाहरण के लिए 'रोज मोंटाग' (रोजेन मोंटाग), 'फ्रांस योजेफ और फ्रांज' (फ्रांज योजेफ श्ट्राऊस), 'हॉफ बानहॉफ' (हाउप्ट बान-होफ) इसी तरह चित्रों की छपाई इतनी खराब है कि इन्हें न शामिल किया जाता तो पुस्तक के साथ कहीं बेहतर न्याय होता. लेकिन इन कमजोरियों के बावजूद यह पुस्तक उन पाठकों के लिए बहुत उपयोगी है जो पश्चिम जर्मनी के बारे में जानने को उत्सुक हैं.

—विजय क्रान्ति

सिनेमा

प्रकृति-प्रेम की ताजगी

फीजी के राष्ट्रीय कवि कमला प्रसाद मिश्र की कविताएं
प्रकाशक सुरेश ऋतुपर्ण वीणा प्रकाशन, दिल्ली-32, कीमत सौ रुपए

कमलाप्रसाद मिश्र की कविताओं से सबसे पहला और सबसे ज्यादा काव्य प्रभाव यह पड़ता है कि फूल-पत्ती, पेड़-पौधे, कोयल-नदी, सागर आदि प्राकृतिक उपादानों की बहुतायत ने उनके काव्य सृजन को प्रेरित किया है. प्राकृतिक दृश्य के सौंदर्य को नपे-तुले शब्दों में आंक देने वाली कला का कमाल उनकी कविताओं के प्रति पाठक को आकृष्ट करता है. फीजी में 1913 में जन्मे इस कवि का किशोरवय भारत में वृंदावन के गुरुकुल में बीता है. लगभग ग्यारह वर्ष तक वे भारत में विद्याध्ययन करते रहे और— आयुर्वेद शिरोमणि' की उपाधि लेकर फीजी चले गए. ब्रजभूमि उनके— काव्य संसार में रच-पच गई. कृष्ण, यमुना, वृंदावन उनकी स्मृति में स्थायी रूप से मौजूद रहते हैं. फलतः उनकी काव्य संवेदना की लगाव प्रेम, सौंदर्य के चित्रों से निर्मित होती रही है.

उन्होंने भारत में रहकर संस्कृत साहित्य के रस-सौंदर्य संस्कार से अपने को संस्कारित किया है. वाल्मीकि-कालिदास की प्रकृति भाव दृष्टि ने उनकी अनुभूतियों को पकड़ रखा है. उनके चेतन-अवचेतन स्तर में भारतीय परंपरा की बांसुरी खुलकर बजती है. वसंत और फूलों का उल्लास का रंग इस कविता की आभा है और प्रेम जल का मुक्त प्रवाह में ही रहे. यह समय हिंदी कविता में छायावादी काव्य मुहावरे के खुल स्फोट का था. प्रसाद, पंत और निराला की प्रतिभा शक्ति से हिंदी कविता में सृजनात्मकता की नई काव्य-भूमि सामने आ रही थी. इसी मिथ सरीखे अनुभूतिप्रवण, संवेदनशील कवि के लिए बच पाना शायद संभव भी नहीं था.

छायावाद केवल कल्पना और आवेग का काव्य ही नहीं था. उसमें स्वाधीनता संग्राम का भारतीय लोकजागरण भी सांस्कृतिक शक्ति से अपना विशेष स्थान रखता था. प्रसाद, पंत और निराला की काव्यानुभूति के रेशे-रेशे में इस नवजागरण का असर है. यही असर प्रसाद, पंत आदि के माध्यम से मिश्र पर भी एक खास छाप छोड़ता है. मिश्र ने अपनी इसी रंगत की कविताओं को यहां रहकर पत्र-पत्रिकाओं में लिखना जारी रखा होता तो वे हिंदी में सुमित्रानंदन पंत की काव्य प्रतिभा का ही दूसरा विस्तार होते. पंत की भांति ही मिश्र की काव्य-वृत्ति कौतूहली है—वह अपने समय और समाज पर एकाग्र नहीं हो पाती. 'वसंतोद्गार', 'कुसुमायुर्ध', 'मन डूब रहा है' 'किसकी स्मृति', 'वसंती सवैया', 'यह ह्रास', 'गहरे जल में' आदि ऐसी कविताएं हैं जिनमें आवेग और आवेश की काफी धमाचौकड़ी है. इन कविताओं में आत्म-सजगता तो है पर आत्मालोचन नहीं है. शिल्प की तराश है पर प्रसाद जैसा समर्थ संस्कृति बोध नहीं है. स्मृतियों में उमड़ता अतीत मिश्र के लिए कोई तनाव पैदा नहीं करता. वयस्क अनुभूतियों का तगड़ा रेला इस काव्य को चुनौती नहीं देता. जीवनानुभूतियों के गहरे धक्के से 'ताजमहल' जैसी कविता भी सोचने को मजबूर नहीं कर पाती. बस, प्रकृति का एक स्वप्नलोक इस काव्यात्मकता में मौजूदगी रखता है. इसलिए किसी बड़े काव्य प्रयोग की 'आहट' इन कविताओं में नहीं है. ज्यादातर कविताएं अनुभवों को बटोरती भर हैं. उन्हें 'रच' नहीं पातीं. इसलिए कवि की कविता के प्रति सहानुभूति तो उमड़ती रहती है पर काव्यात्मकता से पाठक आश्वस्त नहीं हो पाता.

फिर कवि के मन में तुक का बड़ा मोह है—उदाहरणार्थ 'पता नहीं' कविता में 'सजीव गीत छिप गया/अभिन्न मीत छिप गया/पता नहीं पता नहीं/किधर अतीत छिप गया/' (पृ. 29). ऐसे ही 'जय मेवाड़' कविता में 'यह सुंदर मेवाड़ भूमि है यहां न जाना भूल/चढ़ा देना श्रद्धा के फूल/पावन है यह भूमि और पावन है इसकी धूल/' (पृ. 35). तुक के चक्कर में काव्यात्मकता की बलि दे दी गई है.

इस संग्रह की कविताओं में 'फीजी' प्रेम की अनुराग धारा का होना स्वाभाविक ही है. इनमें कवि की आत्मभिव्यक्ति भी खासी शक्तिशाली है. लेकिन जब मिश्र 'अमिताभ! नाचो', 'लाल किला में कवि सम्मेलन', 'दान देने की शर्त', 'दिल्ली में', 'हरे कृष्णा हरे रामा', 'दाढ़ी का प्रभाव', 'गुरु चेला', 'दम मारो दम' जैसी कविताएं लिखते हैं तो काव्य जिज्ञासा का स्तर गिर जाता है. विडंबना यह है कि इन कविताओं में काव्यात्मकता और नाट्यात्मकता का सहज सामंजस्य नहीं हो पाता. भाव या विचार मात्र एक 'वर्णन' बनकर रह जाता है. कवि को 'दिवाली', 'वह होली', 'मथुरा', कृष्णाजन्म-स्थान', 'बंबई', 'यह दिल्ली है' जैसी रचनाओं में भावान्वित की सफलता नहीं मिली.

जाने क्यों इस संग्रह को शुरू से आखिर तक पढ़ने के बाद लगता रहा है कि मिश्र में भाव विस्फोट की जो ताजगी आरंभिक छायावादी तकनीक की कविताओं में थी— वह बाद में कुम्हलाती चली गई है. न केवल काव्यानुभूति बल्कि शिल्प की चमक भी गायब होती गई. हां, इधर जब कभी वे अनुभव के भरोसे पर कविता लिखते हैं तो उसमें जीवन वास्तव में काफी गाढ़ा होता है. कवि की मौलिक संवेदना का रूप-रंग भी किसी गहन रासायनिक परिवर्तन का संकेत देता है. यह कवि न तो बिंबों की आतिशबाजी करता है, न ही प्रतीकों का चौंकाने वाला संसार रचता है. मिश्र मूलतः प्रकृति प्रेमी कवि हैं. उनकी काव्य संवेदना में मानव का हस्तक्षेप ज्यादा नहीं है. जीवन की जटिल अनुभूतियां भी कवि स्वभाव की सतह पर ही सक्रिय रहती है, भीतर से पुकारती, हुंकारती हुई आती प्रतीत नहीं होती हैं.

फिर भी इस प्रवासी भारतीय कवि की चित्रात्मक कल्पना में मानव मन को उद्वेलित करने की शक्ति है. इन कविताओं में भारत प्रेम और देश भक्ति-राग-रस भरा हुआ है. मिश्र की इन कविताओं का भारतीय पाठक को स्वागत करना चाहिए क्योंकि ये मानव प्रकृति प्रेम की कविताएं हैं.

—कृष्णदत्त पालीवाल

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उत्तर प्रदेश

'आज' का 'जागरण' युद्ध

दो दिग्गज अखबारों की सिर फुटव्वल से सरकार खुश

उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख हिंदी दैनिकों में इन दिनों घमासान युद्ध चल रहा है. कोशिश है प्रतिद्वंद्वी से अपने को श्रेष्ठ बताने की. 4.30 लाख रोजाना बिक्री वाले 'आज' और 3.96 लाख प्रसार संख्या वाले 'दैनिक जागरण' की इस लड़ाई का प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री बीरबहादुर सिंह खूब लुत्फ उठा रहे हैं. दोनों के मालिकों के बीच सुलह के लिए 4 जनवरी को हुई बातचीत नाकाम रहने के बाद झगड़ा और भड़क उठने का अंदेशा दिख रहा है.

दोनों अखबारों के बीच मई में फूटी कलह की चिंगारी अब दावानल बन चुकी है. इस साल के शुरू से लेकर अब तक दोनों अखबार समूह कानपुर पुलिस में कुल जमा 63 एफआइआर दर्ज करवा चुके हैं. इनमें से 54 को सिर्फ 'जागरण' समूह ने ही दर्ज कराया है. झगड़े की आंच दोनों के गोरखपुर और आगरा संस्करणों को भी लग चुकी है. अखबारों की प्रतियां लूटने, गड़बड़ी पैदा करने के लिए अपराधियों का खुलकर इस्तेमाल, हॉकरों की पिटाई, संपादकीय कर्मचारियों से हाथापाई और दोनों समूहों के आकाओं को जान से मारने की धमकियां तक देने के आरोप-प्रत्यारोप धड़ल्ले से उछल रहे हैं.

दोनों अखबार एक दूसरे के खिलाफ विषवमन करने में इतने ज्यादा लिप्त हो गए हैं कि सरकार विरोधी खबरें छापने की अपनी परंपरा भी उन्होंने बिसार दी है. एक मौके पर तो मुख्यमंत्री की नजरे-इनायत हासिल करने के लिए दोनों ने उनकी तारीफों के पुल तक बांध दिए.

हालांकि दोनों अखबारों के मालिक-संपादक सकारात्मक प्रचार हासिल करने की सरकार की तिकड़मबाजी से इनकार करते हैं पर 'जागरण' शृंखला के मालिक और संपादक 55 वर्षीय नरेंद्र मोहन का आरोप है कि, "हालांकि हम सरकार को शुरू से ही सारी बातें बताते रहे पर ये हालात पैदा होने देने में उसकी भूमिका बहुत गंदी रही है."

अगस्त 1985 में 'आज' के स्थानीय संपादक विनोद शुक्ल द्वारा इस्तीफा देकर 'जागरण' के लखनऊ संस्करण का संपादन संभाल लेने से यह झगड़ा भड़क उठा था. कानपुर 'आज' के 40 से ज्यादा संपादकीय कर्मचारी भी जल्दी ही शुक्ल के पदचिन्हों पर चल पड़े. नतीजतन सितंबर में 'आज' का कानपुर संस्करण 12 दिनों तक निकल ही नहीं पाया. वाराणसी मुख्यालय वाले 'आज' समूह के प्रधान संपादक और मालिक 32 वर्षीय शार्दूलविक्रम गुप्त का आरोप है कि समूची योजना बहुत सावधानी से तैयार की गई थी. पर शुक्ल कहते हैं, "पत्रकार हमेशा अच्छी नौकरियों के इच्छुक रहते हैं."

इस वाकये के बाद दोनों अखबारों के लोगों के आने-जाने का सिलसिला आम हो गया. कानपुर 'आज' ने जब फरवरी 1987 से हॉकरों को पटाने के लिए उनका कमीशन 30 से 33.33 प्रतिशत कर दिया तो मामला तूल पकड़ गया. मई से हॉकरों ने 'जागरण' के रविवारीय संस्करणों का बहिष्कार शुरू कर दिया क्योंकि जागरण वालों ने कमीशन बढ़ाने से इनकार कर दिया था. नरेंद्र मोहन कहते हैं, "आज वालों ने हॉकरों का कमीशन बढ़ाकर सितंबर 1985 में कानपुर के अखबार प्रबंधकों के बीच हुआ करार तोड़ा है."

'जागरण' ने इंडियन ऐंड ईस्टर्न न्यूजपेपर्स सोसायटी (आइईएनएस) को शिकायत की तो उसने पिछले साल 17 जुलाई को लखनऊ में आयोजित अपनी बैठक में, 'आज' द्वारा हॉकरों का कमीशन बढ़ाने और प्रतिद्वंद्वी अखबार के खिलाफ उनको भड़काने की कार्रवाई की निंदा कर दी. आइईएनएस ने मामले की पड़ताल के लिए पिछले साल 21 जुलाई को 'अमृत बाजार पत्रिका' के पी.के. राय की अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति भी बना दी. समिति ने अभी रिपोर्ट नहीं दी है.

इस दरम्यान 'आज' ने हॉकरों का कमीशन फिर बढ़ाकर 37.5 प्रतिशत कर दिया. प्रदेश में हॉकरों को मिलने वाला यह अधिकतम कमीशन है. उनके हौसले बुलंद हो गए हैं और अब वे सब जगह 37.5 फीसदी कमीशन के लिए राज्यव्यापी हड़ताल करने की योजना बना रहे हैं. उत्तर प्रदेश समाचार विक्रेता संघ के अध्यक्ष क्रांति कुमार कहते हैं, "यदि 'आज' इतना कमीशन दे सकता है तो बाकी अखबारों को भी बिक्री बढ़ाने के लिए इतना कमीशन देना चाहिए."

कानपुर, 'जागरण' की फिलहाल 1.17 लाख और 'आज' की 1.09 लाख प्रतियां बिक रही हैं. नतीजतन प्रतिस्पर्धा और तीखी हो उठी है. दोनों अखबार मुस्तैदी से अपने हॉकरों की हिफाजत कर रहे हैं. लग रहा है कि दोनों अखबारों की जंग अभी चलेगी. राज्य सरकार के लिए इससे खुशी की और क्या होगी.

—बिलीप अवस्थी, कानपुर, वाराणसी से

नरेंद्र मोहन
मालिक-संपादक, 'दैनिक जागरण'

दोनों अखबार एक दूसरे के खिलाफ विषवमन में इतने लिप्त हो गए हैं कि सरकार विरोधी खबरें छापने की अपनी परंपरा भी उन्होंने बिसार दी है

शार्दूलविक्रम गुप्त
मालिक, 'आज'

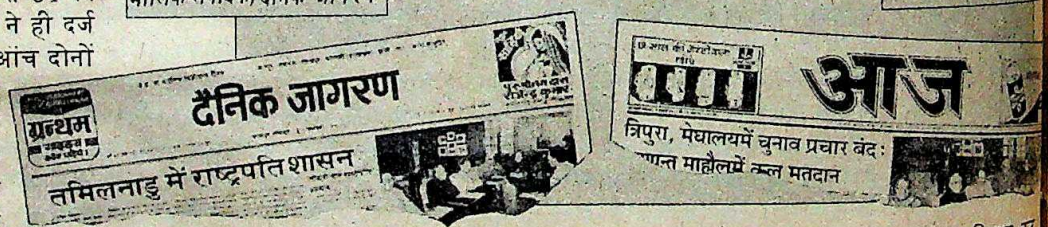

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कानपुर

गंगा एक, भगीरथ अनेक

नदी को फिर शहर के करीब लाने के कई खतरे भी

उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भारी सिरदर्द पैदा हो गया है. कानपुर की जनता ने शहर से दूर खिसक चुकी गंगा को फिर से इस औद्योगिक नगरी की ओर मोड़ने का बीड़ा उठा लिया है. इस परियोजना के प्रति सरकार की सुस्ती से नदी के प्रवाह को मोड़ने का काम 15 मार्च से शुरू करवा देगी.

लेकिन शहर के लोग ऐसे आश्वासनों की असलियत पहचानते हैं. इसलिए उन्होंने अपना काम जारी रखने का फैसला किया. अब यह मुद्दा इतना गंभीर हो उठा है कि सरकार के पास इसे रोकने के लिए न तो नैतिक बल है और न ही साहस.

मुख्यमंत्री वीरबहादुर सिंह प्रशासनिक स्तर पर इस समस्या को भले ही न सुलझा पाए हों पर राजनैतिक स्तर पर उन्होंने बहुत फुर्ती दिखाई. उन्हें पता चल चुका था कि भाजपा, लोकदल (अ) और लोकदल (ब) सरीखे अधिकांश विपक्षी दल तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बजरंग दल जैसे संगठन इस जन आंदोलन की पीठ पर हैं और इसे कुछ गण-मान्य लोगों का भी समर्थन हासिल है.

इस 'कार सेवा' में लगे विपक्षी नेताओं से नीचा न दिखने की आकांक्षा में मुख्यमंत्री ने 26 जनवरी को 'गंगा महायज्ञ समिति' के दो प्रमुख आयोजकों—स्वामी परमानंद और उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्यामबिहारी मिश्र की खूब सराहना की. उन्होंने कहा, "आप सराहनीय काम कर रहे हैं. मैं भी किसी दिन इस 'कार सेवा' में भाग लूंगा."

जनता गंगा को फिर से अपने शहर में बहती देखने को उत्सुक है. समिति के नेता भी बड़ी होशियारी से काम ले रहे हैं. वे इस बात के प्रति सावधान हैं कि कहीं यह महज एक हिंदू आंदोलन न बनकर रह जाए. नतीजतन, स्थानीय सिख संत बाबा मोहन सिंह अपने करीब 500 अनुयायियों समेत खुदाई के काम में कूद पड़े हैं. उनके साथ ही कुछ जाने-माने मुस्लिम स्कूलों के अनेक नौजवान भी इसमें भाग ले रहे हैं.

1962 में प्रस्तावित और फिर 1973 में औपचारिक तौर पर स्वीकृत गंगा बांध परियोजना पर अमल में देरी की जिम्मेदारी जितनी इंका की भीतरी लड़ाई पर आती है उतनी ही नौकरशाही की उदासीनता भी इसका सबब रही है. 1948 तक गंगा कानपुर की उत्तर-पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती थी. लेकिन धीरे-धीरे पानी का बहाव दूसरे तट की ओर यानी उन्नाव जिले की ओर सरक गया.

प्रवाह बदल जाने से शहर में पीने के पानी की किल्लत पैदा हो गई. इस समस्या की जांच के लिए कई समितियां गठित हुईं. पहली समिति केंद्रीय जल और बिजली आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष एम.आर. चोपड़ा की अध्यक्षता में बनी. इसका काम न सिर्फ पेयजल उपलब्ध कराने बल्कि नदी

नहर खोदते स्वयंसेवक और (सबसे ऊपर) स्वामी परमानंद: पक्का इरादा

आजिज आकर लोगों ने हरिद्वार के 63 वर्षीय स्वामी परमानंद की सरपरस्ती में 4.5 किलोमीटर लंबी नहर खोदने का काम शुरू कर दिया. मध्य जनवरी में जब कुछ स्वयं-सेवकों और स्थानीय व्यापारियों ने यह काम हाथ में लिया तो सरकार ने इसे हंसी-खेल ही समझा. लेकिन हफ्ते भर बाद करीब 20 हजार लोग जब इसमें जुट गए तो सरकार चौकन्नी हो उठी. 24 जनवरी को लखनऊ के एक संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री वीरबहादुर सिंह ने इसे 'राजनीति से प्रेरित' बताया. पर अगले ही दिन इसके पीछे भारी जन-समर्थन देखते हुए उन्हें अपने शब्द वापस लेने पड़े. उन्होंने आयोजकों को आश्वासन दिया कि सरकार खुद

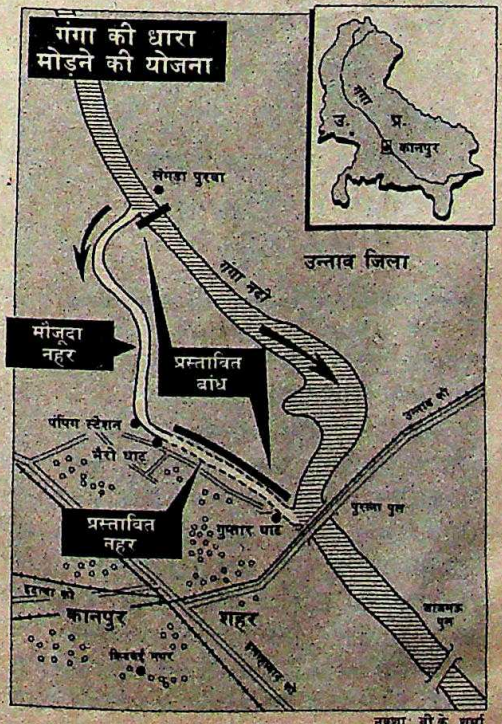

नक्शा: बी.के. शर्मा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

के तट पर एक बिजली संयंत्र स्थापित करने की योजना तैयार करना भी था. 1965 में समिति ने अपनी रिपोर्ट में पानी की समस्या से निबटने के लिए सुझाव दिया कि भैरो घाट के पास बांध बनाकर वहां एक जलाशय खुदवा दिया जाए.

एक और समिति ने भी इन्हीं प्रस्तावों का समर्थन किया. गहन सर्वेक्षण के बाद 1973 में वह इस नतीजे पर पहुंची कि परियोजना पर 22.88 करोड़ रुपए खर्च होंगे. समिति का सुझाव था कि परियोजना से हासिल 12,000 एकड़ जमीन बेचकर वह 21.8 करोड़ रुपए कमा सकती है.

इन्हीं रिपोर्टों के आधार पर 1973-74 में तत्कालीन स्वायत्त शासनमंत्री बेनी सिंह अवस्थी ने परियोजना पर काम शुरू करने के लिए 80 लाख रुपए मंजूर किए. यह रकम सिंचाई विभाग को दी गई. विभाग ने बांध की प्रस्तावित जगह पर पांच लाख रुपए की लागत से तीन खंभे खड़े करवाए. परियोजना कुछ आगे बढ़ती, इससे पहले ही सरकार बदल गई और हेमवतीनंदन बहुगुणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे. उन्होंने धन की कमी बताते हुए काम रुकवा दिया.

1981-82 में फिर इस काम के लिए एक करोड़ रुपए निर्धारित किए गए लेकिन तब इंका नेताओं की आपसी खींचतान शुरू हो गई. परियोजना के प्रबल विरोधी केंद्रीय सिंचाई राज्यमंत्री जिया-उर-रहमान अंसारी थे. इसी खींचातानी में आबंटित रकम की मियाद पूरी हो गई. लेकिन उत्तर प्रदेश के स्वायत्त शासन विभाग ने 1982-83 के बजट में इस परियोजना के लिए पैसा फिर आबंटित कर दिया. पर परियोजना चूंकि केंद्रीय सिंचाई मंत्रालय के अधीन आती थी इसलिए वह इसे लटकाए रखने में कामयाब हो गया. और तब से ही पूर्व केंद्रीय मंत्री आरिफ मुहम्मद खां और इंका महासचिव नरेशचंद्र चतुर्वेदी जैसे कानपुर के नेता इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए जुटे रहे पर उन्नाव के इंका नेता पलीता लगाकर ही माने.

योजना में अंसारी की दखलंदाजी से पहले आठ सरकारी समितियों ने सुझाव दिया था कि बांध या तो भैरो घाट पर या उसके नजदीक बनाया जाना चाहिए. लेकिन 1982 में खुद अंसारी द्वारा गठित एक समिति ने सुझाव दिया कि यह बांध मुर्दा घाट पर बनाया जाना चाहिए. यह प्रस्ताव उन्नाव के जमींदारों के लिए तो सुविधाजनक था लेकिन इससे कानपुर निवासियों की समस्याओं का कोई हल नहीं निकलता था. इंका नेताओं का झगड़ा चलता रहा और इस दौरान योजना की लागत 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर गई.

15 बरस पुरानी गंगा बराज समिति उन कुछ स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं में से एक है जो इस मामले को हरदम उठाती रही. समिति के अध्यक्ष और पूर्व निगम पार्षद सी.एम. सदरी कहते हैं, "नेताओं, खासकर अंसारी के इरादे स्थानीय लोगों के लिए घातक साबित हुए हैं."

फिलहाल तो नदी से सात किलोमीटर लंबी नहर के जरिये पानी लेकर भैरो घाट बिजलीघर के नजदीक बने जलाशय में डाल दिया जाता है. पानी का बहाव बनाए रखने के लिए पूरी नहर के बराबर निष्कासन उपकरण भी लगे हैं. इस पर सालाना 25 लाख रुपए लागत आती है.

समिति के नेताओं की वर्तमान योजना गुप्तार घाट से भैरो घाट तक 4.5 किलोमीटर लंबाई में 80 फुट चौड़ी और 12 से 15 फुट गहरी नहर बनाने की है. इसे वर्तमान नहर से जोड़ दिया जाएगा. समिति लंगड़ा पुरवा के नजदीक नदी पर एक बांध बनाकर पानी नहर की ओर मोड़ देने की भी सोच रही है. दरअसल उनकी योजना दो बांध बनाने की है—एक लंगड़ा पुरवा पर और दूसरा निर्माणाधीन नहर के समानांतर नदी तल में.

फिलहाल नदी से 61.89 क्यूसेक पानी की निकासी होती है जबकि नहर में सिर्फ 2.53 क्यूसेक पानी ही समा सकता है. पर नहर इतना पानी नहीं समो सकेगी यह बात समिति नेताओं के गले के नीचे ही नहीं उतर रही. सिंचाई विभाग के एक वरिष्ठ अभियंता का कहना है कि बारिश के दिनों में ये बांध पानी का स्वाभाविक बहाव रोक देंगे. उससे कानपुर और उन्नाव जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ आ सकती है.

लेकिन स्वामी परमानंद पर इन दलीलों का कोई असर नहीं. दृढ निश्चय से वे कहते हैं, "या तो सरकार इस काम को हाथ में ले या फिर हम गंगा को कानपुर लाकर रहेंगे." कानपुर के 160 व्यापार संघों का प्रतिनिधित्व करने वाले मिश्र और उनके सहयोगी व्यवसायी भी ऐसी ही बात कहते हैं. शहर के ये व्यापार संघ योजना के लिए प्रतिदिन 200 मजदूर मुहैया कराते हैं. तो क्या शहर का कामकाज अब भीड़ ने संभाल लिया है? कानपुर के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बी. बी. सिंह तल्खी से जवाब देते हैं, "सरकार जल्द ही दखल देगी और फिर सब ठीक हो जाएगा."

प्रशासन को शायद इसी बात का इंतजार है कि कब जनता का जोश ठंडा पड़े और वह काम को अपने हाथ में ले. यदि सरकार की यह उम्मीद पूरी नहीं होती तो आने वाली बारिश में इस औद्योगिक शहर के सामने कई समस्याएं मुंह बाये खड़ी हो सकती हैं.

—दिलीप अवस्थी

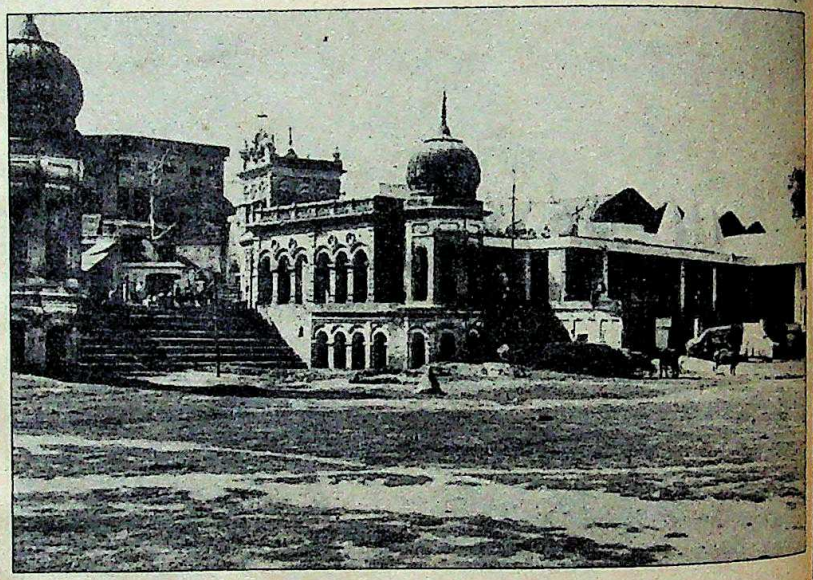

कानपुर के सूखे पड़े घाट

सरकार की सुस्ती से तंग आकर लोगों ने गंगा का रुख कानपुर की ओर मोड़ने के लिए 4.5 किमी नहर खोदने का बीड़ा खुद उठा लिया

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पश्चिमी घाट

बंजर पहाड़ों की परिक्रमा

वन विनाश की ओर ध्यान खींचने के लिए पदयात्रा

"अब हमारे राज में पत्थरों और बालू के ढेर ही रह जाएंगे" —एक मराठी लोकगीत

उन्हें देखकर किसी बहुरंगी टोली का भान होता था. कपड़े के झोले टांगे, रबड़ की चप्पलें पहने और 'जंगल बचाओ' लिखे बैनर उठाए वे पश्चिमी घाट की बंजर पहाड़ियां सर करते आगे बढ़े जा रहे थे. बीच में कभी वे गाना गाने लगते, नारे लगाते या फिर गांव वालों से बतियाने लगते. पर ज्यादातर वे चुपचाप ही चले जा रहे थे. जितना वे आगे बढ़ते जाते उतनी ही निराशा उनके चेहरे से टपकने लगती.

"मीलों तक हमें एकदम नंगी भूरी पहाड़ियां ही दिखती थीं. पेड़ कहीं नजर नहीं आते थे. धूप से बचने के लिए पेड़ की छाया के लिए हम तरस गए. रह-रहकर ख्याल उठता है भगवान! हमने यह क्या कर डाला?" यह कहते हुए कैलाश मल्होत्रा भावुक हो उठे. वे मानव-विज्ञानी हैं और पश्चिमी घाट बचाओ' अभियान के अध्यक्ष हैं. इस अभियान के तहत पहाड़ियों की 100 दिन की पदयात्रा पिछले पखवाड़े गोवा के पोंडा में समाप्त हुई. इस अभियान में विभिन्न राजनैतिक, सामाजिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि से जुड़े छह राज्यों के करीब 104 संगठनों ने हिस्सा लिया.

देश की इस सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला की भयंकर स्थिति देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए. अभियान के एक संयोजक ए. मोहन कुमार के मुताबिक इसका सामना 'हमें अनेक वर्षों तक करना पड़ेगा.' पदयात्रियों ने देखा कि प्राकृतिक संपदा के मामले में देश में हिमालय के बाद दूसरे नंबर की यह पर्वत श्रृंखला कैसे योजनाबद्ध तरीके से नष्ट कर दी गई है, प्राकृतिक संपदा पर निर्भर लोगों

चार्ट: बी.के. शर्मा

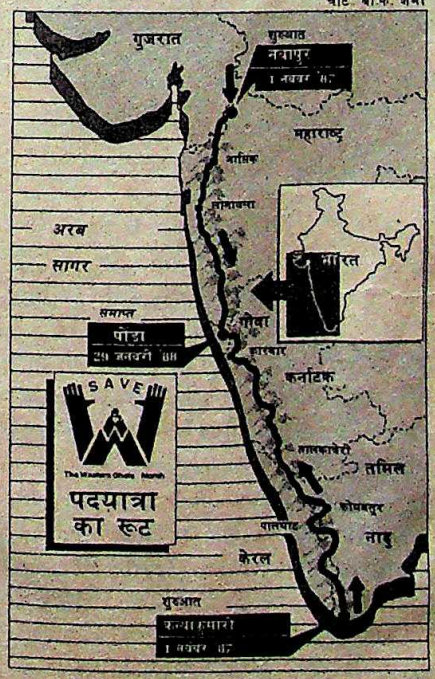

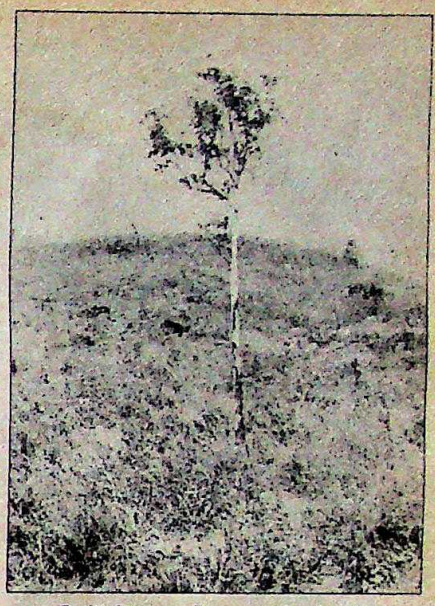

घाटियों से गुजरते पदयात्री (बाएं); और विनाश का प्रतीक इकलौता पेड़

को कैसी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है. कन्याकुमारी जिले की पहाड़ी ढलानों पर पदयात्रियों की भेंट दुबली-पतली येलम्मा से हुई. वह अनपका चावल पानी में भिगोकर खाती है क्योंकि जलावन बहुत महंगा है. वह जंगल से अब लकड़ी भी नहीं बीन सकती क्योंकि वहां पेड़ ही नहीं बचे हैं.

इस पदयात्रा में पूरी दूरी तय करने वाले 30 लोगों का एक खास जत्था था. इसके अलावा 200 से अधिक लोग भी थोड़ी-थोड़ी दूरी तक इसमें शामिल रहे. सभी पदयात्री दो जत्थों में थे. एक जत्था दक्षिणी प्रायद्वीप में कन्याकुमारी से ऊपर की ओर बढ़ने लगा जबकि दूसरे ने गुजरात-महाराष्ट्र सीमा पर नवापुर से यह पदयात्रा शुरू की.

जब ये लोग केरल में पदयात्रा कर रहे थे तो थोड़ी देर के लिए उनका मन खुश हो गया. यहां 'शांत घाटी' के घने जंगल दिखते थे जिन्हें जबरदस्त आंदोलन के चलते इंजीनियरों के बुलडोजरों से बचा लिया गया था. लेकिन जैसे ही वे पेड़-पौधों से खाली अरालवोई मोझी में पहुंचे तो विनाश का दृश्य फिर शुरू हो गया. दो दशक पहले ही यह इलाका हरे-भरे मैदानों और झर-झर करते झरनों से भरा-पूरा था. किसानों को पानी मुहैया कराने वाले तीन बड़े तालाब अब सूख गए हैं.

इस विनाशलीला का सबसे खराब असर वनवासियों पर पड़ा है. क्विलोन में पदयात्रियों की भेंट मलमंपडरम नामक घुमंतू जाति के लोगों से हुई. ये लोग जंगल से शहद इकट्ठा करते हैं और टोकरी बनाने के लिए सरकंडा बिनते हैं. लेकिन जंगल खाली

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हो जाने से अब न उन्हें भोजन के लिए कंद-मूल मिलते हैं, न शहद और न ही सरकंडा. इनके पुनर्वास के लिए सरकार ने 45 मकान बनाए जिनमें अधिकांश गुसल-खाने से बड़े नहीं हैं. इन मकानों में से आधे तो दो साल में ही गिर गए.

पदयात्रियों को कई मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा. दक्षिण से चलने वाले जत्थे को जंगलों, बागानों और बंजर जमीन से गुजरते समय जोंकों, मच्छरों और दूसरे कीड़ों ने काट खाया. हर 20 किलोमीटर पर जलवायु में परिवर्तन के कारण यात्रियों को कभी स्वेटर पहनना पड़ता तो कभी उतार देना पड़ता था. उन्हें असंख्य झरनों को पार करते आगे बढ़ना पड़ता इसलिए उनके बदन के कपड़े कभी सूखे ही नहीं. पारमीबीकुलम से पालघाट तक आसपास कोई गांव न होने की वजह से 50 किमी की यात्रा उन्हें बिना खाए-पिए ही करनी पड़ी. लेकिन जैसा कि एक यात्री ने कहा भी, "उस दौरान अपने साथ ले गए चिवडा और केला ही हमारे लिए सबसे स्वादिष्ट भोजन था."

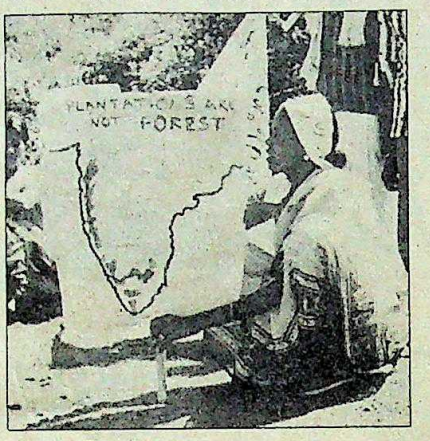

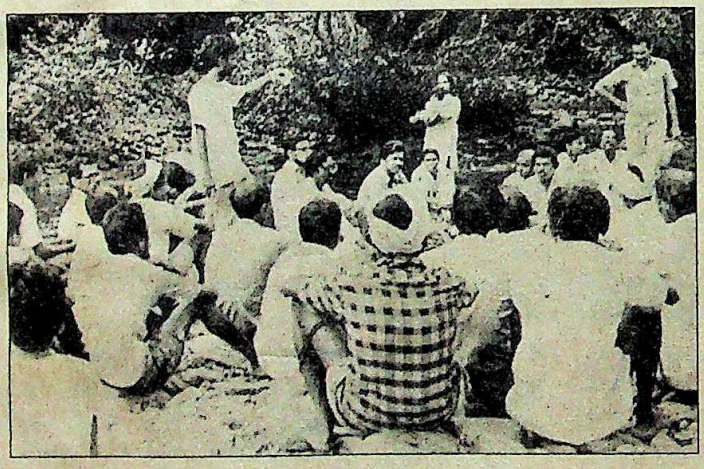

इस बीच नवापुर से चलने वाले उत्तरी जत्थे को अलग ही स्थिति का करीबी अनुभव हुआ. विना पेड़-पौधों के, टूटे-फूटे पिरामिडों से दिखने वाले समतल पठारों पर चलते हुए वे सीकरी तालुके में एक छोटे से जंगल में जा पहुंचे. इसका मालिक वनवासी पेरिया-मील है. जंगल का अपना घर-बार लुट जाने के बाद उसने स्थिति सुधारने का फैसला किया. आठ साल पहले उसने छह एकड़ खाली पड़ी सरकारी जमीन में 32 किस्म के पौधों के बीज छिड़क दिए. मवेशियों, आदमियों और कीट पतंगों से उसने इन पौधों की रखवाली की. उस जमीन में फिर से जंगल उग आया. लेकिन जब पदयात्री दक्षिण की ओर बढ़े तो फिर वही विनाश का दृश्य शुरू हो गया.

लंबी यात्रा के बाद उत्तर और दक्षिण के दोनों जत्थे गोवा की पहाड़ियों पर सारे अभियान का लेखा-जोखा करने के लिए जुटे. उनका ध्यान इस पर केंद्रित रहा कि पेड़ों की कटाई से जंगलों के आसपास बसे लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ा है. जिन 116 गांवों का सर्वेक्षण किया गया उनमें एक समान समस्याएं पाई गईं.

ज्यादातर गांवों में पीने के पानी वाले कुएं तेजी से सूखते जा रहे हैं. लोगों को पानी के लिए अब एक से दस किलोमीटर तक जाना पड़ता है. जंगलों के खत्म होते जाने से जलावन और चारे की समस्या दिनोदिन गहराती जा रही है. जलावन बटोरने के लिए औरतों को औसतन पांच किलोमीटर तक जाना पड़ता है. करीब आधे गांवों में झोंपड़ियों के लिए न बांस-बल्लियां

'बगीचे जंगल नहीं': विरोध की तख्ती; और गांव वालों के साथ पदयात्री

मिलती हैं और न छप्परों के लिए खर-पतवार. सर्वेक्षण में लिए गए कुल गांवों में से एक तिहाई में कम बारिश और भू-क्षरण के कारण पैदावार काफी कम हो गई है. सबसे दुखद तो यह है कि किसी भी एक गांव के करीब आधे लोग रोजी-रोटी की तलाश में दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं. वे शहर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं.

पदयात्रा में शामिल एक जाने-माने पर्यावरणविद माधव गाडगिल कहते हैं, "हम महसूस करने लगे हैं कि जल्दी ही हमें न सिर्फ भोजन पकाने के लिए जलावन से वंचित होना पड़ेगा बल्कि पीने और खेतों को सींचने का पानी भी उपलब्ध नहीं होगा. न ही मवेशियों को चारा मिलेगा. यह साफ हो गया है कि जंगल ही खत्म नहीं हो रहे बल्कि इसके आसपास रहने वाले लोगों के अस्तित्व पर भी खतरा बन आया है."

पर यह पदयात्रा भी विवादों से अछूती नहीं रही. कई विख्यात पर्यावरण दलों ने अपने को इससे अलग रखा. कश्मीर से कोहिमा की पदयात्रा से प्रसिद्धि पाए सुंदरलाल बहुगुणा को पहले कन्याकुमारी वाले जत्थे को हरी झंडी दिखानी थी. लेकिन बाद में वे विरोध जताते हुए अलग हो गए कि इस पदयात्रा के लिए पर्यावरण विभाग से पैसा मिला है. लेकिन आयोजकों का कहना है कि पर्यावरण विभाग ने इसके लिए 3.8 लाख रुपए का अनुदान तो जरूर दिया पर वह बिना शर्त था. एक अन्य शक्तिशाली पर्यावरण संगठन केरल शास्त्र साहित्य परिषद भी राष्ट्रीय विज्ञान चेतना कार्यक्रम में व्यस्त रहने के कारण शामिल नहीं हुआ.

तमाम असुविधाओं के बावजूद पदयात्रा से दक्षिणी प्रायद्वीप के पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण पश्चिमी घाट की उपेक्षा की तरफ लोगों का ध्यान गया है. पर देश के पर्यावरण के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हिमालय पर विनाश की यह प्रक्रिया अभी जारी है. इस पदयात्रा में शामिल लोगों को यह एहसास हुआ है कि इससे भी बड़ा काम अभी बाकी है. इसके एक संयोजक कलानिधि मणि कहते हैं, "जहां भी हम गए, गांव वाले इस विनाश से नाराज और परेशान मिले. हमें लगा कि इस समस्या को उठाना ही काफी नहीं बल्कि इसके लिए सक्रिय होकर कुछ करना भी जरूरी है."

और सचमुच यही कुछ करने का बीड़ा उन्होंने उठाया है. गोवा के समापन सत्र में 'पश्चिमी घाट बचाओ संगठन' बनाया गया जिसकी शाखाएं सभी प्रभावित राज्यों में बनाई जाएंगी. यह संगठन लोगों को पेड़ लगाने और जंगल काटने के खिलाफ संघर्ष में सहायता देगा. वह देश की पर्यावरण नीतियां बदलवाने की मुहिम भी चलाएगा. संगठन के संयोजक जगदीश गोडबोले कहते हैं, "यह सिर्फ पदयात्रा ही नहीं रही बल्कि अब पश्चिमी घाट को बचाने का एक आंदोलन बन गया है." और यह आंदोलन पत्थरों और बालू के ढेर को हरे-भरे मैदानों में बदलने का ही आंदोलन है.

—राज वेंगप्पा, पोंडा से

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आखिर क्यों ज्यादा से ज्यादा लोग शादी-ब्याह के अवसर पर बीनाटोन क्वार्ट्ज टी.वी. ही उपहार में दे रहे हैं... ।

...सामंजस्य के लिए जिसकी गारंटी है।

अपने प्रिय से प्रिय व्यक्ति को दीजिए वह उपहार जो सर्वोत्तम हो। और अनूठे बीनाटोन क्वार्ट्ज टी वी से बेहतर उपहार भला क्या हो सकता है। रंगों की मोहकता तथा तस्वीर की स्पष्टता का बेमिसाल सामंजस्य और पिक्चर ट्यूब पर 3 साल की गारंटी भी। अपने निकटतम रंगीन/ब्लैक ऐण्ड व्हाइट टी वी के डीलर के यहां बीनाटोन के विविधतम मॉडलों को देखिए।

एक ऐसा उपहार जिसके लिए आप हमेशा याद किये जाएंगे।

बीनाटोन के सभी उत्पादनों को मास्टरकेयर का सहारा प्राप्त है जो बस एक फोन करते ही देशव्यापी बिक्री-बाद-सेवा प्रदान करते हैं।

Binatone

बनावट बेमिसाल, साथ निभाए सालोंसाल

बीनाटोन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लि., 23/4788-90 अंसारी रोड, दरियागंज, नयी दिल्ली-110002.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ऊपर से देखिए ...है

ऊपर से देखकर कार के खुलेपन का सही अन्दाज़ा लगाया जा सकता है। ऐसा बहुत कम लोग करते हैं, और ऐसा जरूरी भी नहीं, परन्तु इससे ओमनी के विस्तृत स्थान का एहसास होता है। सिर के ऊपर का, टांगे फैलाने का, ढेर-सा सामान रखने का स्थान, खेल-कूद की सामग्री और लोगों के बैठने की जगह।

जिस कार में शानदार बनावट, ठोस कार्यकुशलता, ईंधन का कुशलतम उपयोग और कार चलाने के असीम आनन्द के साथ-साथ आरामदेह खुली जगह भी हो तो उसे एक 'सम्पूर्ण' कार की संज्ञा दी जा सकती है। तभी तो इसे 'ओमनी' (अंग्रेजी भाषा का शब्द, जिसका अर्थ है- सर्वांगीण) नाम दिया गया है। आइए अब नीचे आकर इसकी खूबियों को गौर से देखें

भीतरी-भाग: अनेक उपयोग

एक आम गणना के अनुसार ओमनी के भीतर का क्षेत्र 7.5 क्यूबिक मीटर है। पिछली सीट हटा दीजिए। लीजिए मारुति ओमनी सामान ले जाने वाली वैन, छोटे की गाड़ी या दूसरे शहर में जाने के लिए बड़ी कार के रूप में तैयार।

फिर भी आपके लिए यह फैमिली कार, ऑफिस कार, तथा शहर में दूर-दूर जाने वाली सुदृढ़ कार बनी रहती है।

वास्तव में, इसमें इतना अधिक स्थान होने की बदौलत आप इसका उपयोग कर सकते हैं।

मारुति ओमनी—चलाने में आराम

ओमनी चलाने का आनन्द ही कुछ और है। इंस्ट्रूमेन्ट पैनल सुन्दर और सुविधाजनक है। स्टीयरिंग कॉलम की पोज़ीशन बिल्कुल सही। सीटों में फेर-बदल सम्भव है। कन्ट्रोल लीवर तथा गियर शाफ्ट हाथ से छू लेने वाली दूरी पर।

और हाँ, सांस लेने के लिए भी बहुत खुला स्थान।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

A 5394 H

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ओमनी

आज की सबसे खुली कार!

का अति कार्यशील सुज़ूकी इंजन

पर 3 सिलेंडर, 4 स्ट्रोक, 800 सी सी का इंजन। अन्य शब्दों में यह है से श्रेष्ठ कार्यकुशलता और उच्च क्षमता वाला इंजन। इसे बिना-परेशानी ,000 किलोमीटर तक आराम से चलाया जा सकता है। इसके बाद इसे 'री-बोर' किया जा सकता है।

की विशेषताएं

और मज़बूती मारुति की अनिवार्य विशेषताएं हैं, जबकि महत्त्वपूर्ण बात यह है ऐसी खूबियां अधिक मंहगी कारों में पाई जाती हैं।

- एक स्वतंत्र मैक्फ़र्सन स्ट्रट सस्पेंशन–अगली तरफ़, तथा लीफ़-स्प्रिंग टाइप सस्पेंशन-पिछली तरफ़।
- 30 सेंटीमीटर व्यास के 'ड्राप-सेंटर' पहिए सुरक्षापूर्ण ढंग से घूमने और कम जगह में आसानी से मोड़ने की सुविधा प्रदान करते हैं।
- 'सिंक्रोमेश' फॉरवर्ड गियर तथा दोहरा ब्रेकिंग सर्किट।
- जंग से पूरी तरह बचाव के लिए इलेक्ट्रोफ़ोरेटिक पेन्ट से उपचारित फ्रेमवर्क।
- इंजन ठंडा रखने की विशेष व्यवस्था, जिससे रोज़-रोज़ रेडियेटर में पानी भरने की मुश्किल दूर हो जाती है।

मारुति ओमनी: निःसंदेह एक उत्तम कार। उससे भी उत्तम बात है इसका सबसे खुली कार होना।

(डी.जी.एस. एण्ड डी रेट कॉन्ट्रेक्ट पर भी उपलब्ध)

चित्र में दर्शाया गया सहायक सजावटी/उपयोगी सामान ओमनी की बिक्री में शामिल नहीं।

MARUTI **omni** खुले आराम का सफ़र

मारुति उद्योग लिमिटेड 11 वीं मंजिल, जीवन प्रकाश, 25 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110 001

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गौतम राजाध्यक्ष

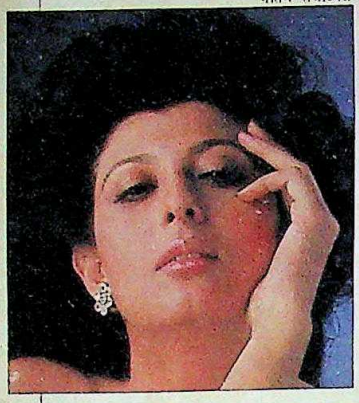

◆ और अब मॉडलिंग से निकलकर फिल्मों की दुनिया में छलांग लगाने की बारी है 1980 की मिस-इंडिया **संगीता बिजलानी** की. सात साल तक वीको, पोंड्स, कालगेट और निरमा आदि के संदेश टीवी के दर्शकों तक पहुंचाने के बाद उन्होंने अपने एक दोस्त की फिल्म में काम किया. यहीं से कैरियर का एक नया दरवाजा खुला और निर्माता जे.पी. दत्ता ने उन्हें अपनी फिल्म 'हथियार' के लिए साइन कर लिया— इस शर्त पर कि वे फिल्म पूरी होने तक कहीं और काम नहीं करेंगी. और अब इस बंधन से मुक्त होते ही वे फिल्में साइन करने के एक नए अभियान में जुट गई हैं. इस फिल्मी परिवर्तन के बारे में वे कहती हैं, "अब से मैं अधिक ध्यान फिल्मों पर ही दिया करूंगी."

◆ भले ही राजनीति और कविता एक-दूसरे के विरोधी खेमों की सदस्याएं हों लेकिन ओडीसा के 61 वर्षीय मुख्यमंत्री जानकी बल्लभ

पटनायक: दोहरी भूमिका

प्रमोद पुष्करणा

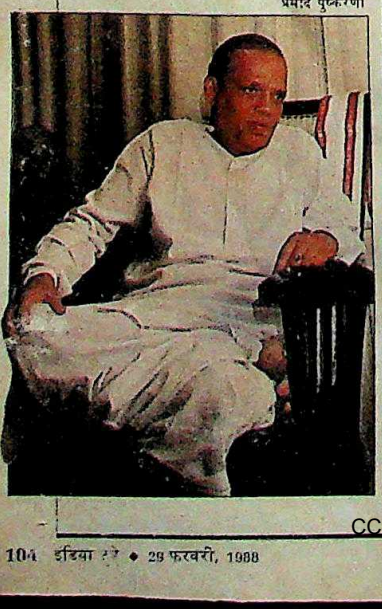

बिजलानी: नया दौर

पटनायक दोनों खेमों में अपने पैर मजबूती से जमाए हुए हैं. सात साल से मुख्यमत्री की गद्दी पर मजबूती से बैठे पटनायक पिछले दिनों अपने कविता संग्रह 'सिधु उपात्यका' (सिधु घाटी) के कारण विरोधियों के हमले का केंद्र बन गए. ये 1948 से 1967 के बीच लिखी गई रचनाए राजनेता के कवि हृदय की एक नई झांकी पेश करती हैं. अपने व्यक्तित्व के इस पहलू के बारे में वे कहते हैं, "इन दिनों राजनीति ऐसी रद्दी हो गई है कि अगर अभिव्यक्ति के लिए साहित्य जैसा रास्ता न हो तो आदमी पागल हो जाए." आजकल वे महाभारत का उड़िया अनुवाद करने में लगे हुए हैं.

◆ फैशन और वह भी उस देश से जो समाजवाद और सर्वहारा के मंत्र का जाप करता हो? पर शायद यही कारण था कि सोवियत फैशन डिजाइनर व्याचेस्लाव जायत्सेव के फैशनेबल कपड़ों ने कामकाजी

जायत्सेव फैशन शो में

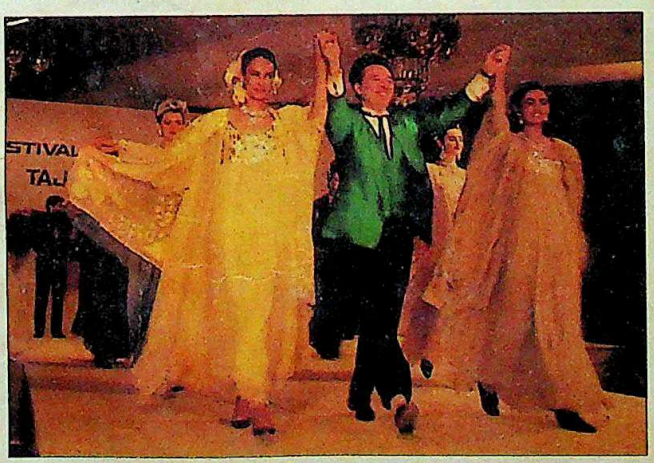

महिलाओं को अधिक आकर्षित किया. 50 वर्षीय डिजाइनर का नजरिया है, "कपड़े ऐसे हों कि पहनने वाली महिला को आराम भी मिले और वह इनमें आकर्षक भी दिखे." भारत में प्रदर्शित उनकी गर्मी की पोशाकें काफी हद तक रुढ़िवादी रुझान वाली थीं— पुरुषों के लिए उनके पास आकर्षक कुर्ते-पायजामे भी थे. और वे खुद भारतीय साड़ी से ऐसे सम्मोहित हुए कि "यह तो ऐसी खूबसूरत चीज है कि मेरे लिए आंखें हटा पाना ही असंभव हो जाता है."

भारी-भरकम केक: आश्चर्य

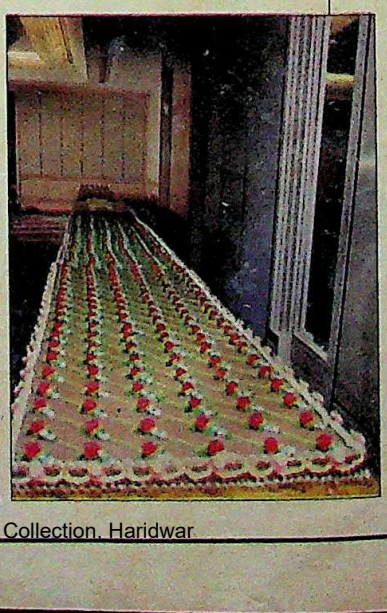

◆ चर्चित फिल्म 'सौदागर' के हिंदुस्तानी हीरो को हिंदी सिनेमा में सफलता के साथ ऐसी आख मिचौनी खेलनी पड़ी कि उसे अपना आशियाना हालीवुड ले जाना पड़ा. वहां कुछ फिल्मों और टीवी सीरियलों में काम करने के बाद अब कबीर बेदी फिर वतन का रुख कर रहे हैं. फिलहाल लौट आने का कारण मारधाड़ भरी फिल्म 'खून भरी

रेखा और कबीर बेदी

मांग' है जिसमें वे रेखा के ऐसे [illegible] की भूमिका निभा रहे हैं जो [illegible] के सामने तो अपनी पत्नी को [illegible] करता है मगर अकेले में उसे [illegible] है. फिल्म के निदेशक राकेश [illegible] कहते हैं, "मुझे ऐसे हीरो की [illegible] थी जो सुंदर हो और निगेटिव [illegible] करने के लिए तैयार हो." [illegible] पत्नी के रूप में शुरुआत करने [illegible] **रेखा** पति की हत्या करके [illegible] चुकाती है. कबीर कहते हैं, "[illegible] यह कैसे हो सकता है कि [illegible] हर रोल चाकलेटी ही हो?"

◆ 52 फीट लंबा और [illegible] किलो का केक. हां, अविश्वसनीय सा लगने वाला ऐसा ही एक [illegible] हाल ही में शिकागो के विल्टन [illegible] ऑफ बेकरी से ग्रेजुएट होकर [illegible] **विशाका श्रॉफ** ने बंबई में [illegible] कराया. उनकी देखरेख में बना [illegible] मेंगिनी पेस्ट्री शॉप के 51 कुशल [illegible] 1425 अंडों, 130 किलो [illegible] 107 किलो मक्खन और [illegible] किलो चाकलेट लगाकर इसे [illegible] किया. और आश्चर्यजनक [illegible] रूप से इसके बनने में [illegible] लगा 'मात्र' 24 घंटे. [illegible] कहती हैं कि इसे बना [illegible] कर 'मैं खुश हुई. [illegible] 400-400 ग्राम के [illegible] 100 रुपए से लेकर [illegible] रुपए तक में बिक्री [illegible] रोटरी क्लब द्वारा [illegible] जित इस पूरे नजारे [illegible] लोगों ने यह कीमत [illegible] 'मीठे' उद्देश्य के लिए [illegible] यह उद्देश्य था. [illegible] रोधी टीका लगाना [illegible] और इसके लिए [illegible] रुपए जुट गए. था [illegible] और 'विशाल' आयोजन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दरबार के दमनकारी

भारी-भरकम कद-काठी के गृहमंत्री बूटा सिंह की अचानक हर जगह तूती बोलने लगी है. जी-हुजूरी और अड़ियलपन जैसे गुणों में पारंगत यह सिख नेता राजनैतिक जोड़तोड़ के मामलों में प्रधानमंत्री राजीव गांधी का मुख्य हथियार बना हुआ है.

आवरण कथा 50

शीतल पेय में उबाल

पंजाब में 22 करोड़ रुपए की एक गैर-प्राथमिकता वाली योजना से अचानक एक राष्ट्रीय विवाद उठ खड़ा हुआ है. पेप्सी कोला के भारत में दाखिल होने के सवाल पर छिड़ी गरमागरम तकरार के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दे भी उठाए गए.

खास रपट 58

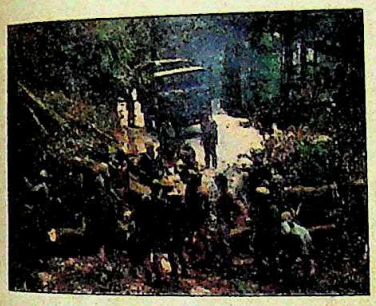

बड़ी बगावत के बगूले

गोरखालैंड आंदोलन बड़ी तेजी से खतरनाक मोड़ लेता जा रहा है. उग्रवादी तत्व आंदोलन के नेता सुभाष घीसिंग के नियंत्रण से बाहर होते जा रहे हैं. ऐसी हालत में अगर विभिन्न पक्षों के बीच कोई समझौता हो भी जाता है तो क्या शांति बहाल की जा सकेगी?

खास रपट 46

हादसे से उपजी हार्दिकता

पांच साल पहले असम में नेल्ली के जघन्य हत्याकांड में अनाथ हुए बच्चे काली रात के उस भयावह दुःस्वप्न को भुलाकर एक सहज जीवन जीना सीख रहे हैं. घृणा और पाशविकता की जगह इनमें शांति और भाईचारे का सहज भाव उपज रहा है.

विशेष लेख 70

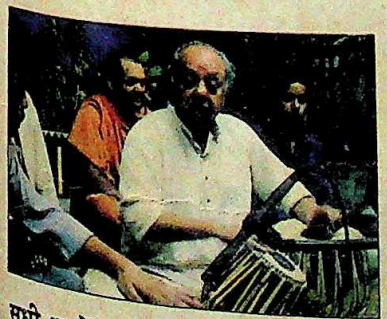

सधी थापों के थिरकते बोल

सुविख्यात तबलावादक उस्ताद अल्लारक्खा और उनके होनहार पुत्र जाकिर हुसैन ने अपनी उंगलियों की सधी थापों से सारी दुनिया के संगीत प्रेमियों को आह्लादित किया है. भारत के महान संगीतकारों पर छायालेखों की कड़ी में एक और छायालेख.

छायालेख 82

परिवर्तन की उम्मीदें

बिहार का बहुप्रतीक्षित नेतृत्व परिवर्तन आखिर पिछले महीने हो ही गया. भागवत झा आजाद को इस राज्य का मुख्यमंत्री बनाए जाने से परिवर्तन की उम्मीदें तो जरूर बंधी हैं पर उनके चयन के लिए अपनाए गए तौर-तरीकों की आलोचना भी हुई है.

आजकल 26

अगले पन्नों पर

कसौटी 13
राजरंग 15
तेवर 17
हिंदोस्तां हमारा 19
बीता पखवाड़ा 21
आजकल
केंद्रीय मंत्रिमंडल: बेकार की उलटफेर 22
बिहार: परिवर्तन की उम्मीदें 26
मध्य प्रदेश: अर्जुन की घर वापसी 28
तमिलनाडु: मतदाताओं पर नजर 30
दिल्ली: वकील नाराज 33
राजस्थान: विपक्षी तलवारों पर सान 34
बिहार: कर्पूरी बिना सून 36
चंद्रास्वामी: फंदे में फंसे गुरु 37
गुजरात: बदलाव के बादल 37
पंजाब: फिर गरम तेवर 38
आखिरी बात 39
विशेष लेख
एक लौहपुरुष का उद्भव 40
राज्य-दर्पण 43
खास रपट
गोरखालैंड आंदोलन:
बड़ी बगावत के बगूले 46
आवरण कथा
गृहमंत्री बूटा सिंह:
दरबार के दमनकारी 50
खास रपट
शीतल पेय में उबाल 58
व्यापार चक्र 65
कारोबार
बजट: एक कष्टसाध्य प्रक्रिया 66
स्कूटर्स इंडिया: बिकने की तैयारी 68
शेयर बाजार 69
विशेष लेख
नेल्ली: हादसे से उपजी हार्दिकता 70
समाचार भाष्यम
सकाल: मिल्कियत का झगड़ा 73
पास-पड़ोस
अफगानिस्तान: गृहयुद्ध के आसार 74
सिनेमा
शहंशाह: विवाद का फल मीठा 76
विज्ञान चर्चा 78
किताबें 79
कला
रईस खां: आखिर घुंघरू टूट गए 80
छायालेख
सधी थापों के थिरकते बोल 82
जगबीती
ब्रिटेन: लौट आए नटराज 94
धरोहर
चंपानेर: तिल-तिल घुलती विरासत 99
चर्चित चेहरे 104

आवरण: रघु राय

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

साइड से भी देखिए ...हैं न

इसमें सन्देह नहीं कि 'ओमनी' देखने में अन्य कारों से अधिक खुली कार लगती है। फिर भी हमने यह बात निश्चित रूप से सिद्ध करने का फैसला किया...और उसे एक साइड से खोलकर आपके सामने प्रस्तुत किया है। देखिए, अब तो यह और भी अधिक खुली लगती है। कितनी जगह है इसमें—सिर के ऊपर की, टांगे फैलाने की, ढेर सा सामान रखने की और लोगों के बैठने की जगह।

जिस कार में मारुति की शानदार बनावट, उत्तम कार्यकुशलता, ईंधन का कुशलतम उपयोग, और कार चलाने के असीम आनन्द जैसी विशेषताओं के साथ इतनी आराम-दायक खुली जगह भी हो, तो मानना पड़ेगा कि इस एक कार में हैं सभी विशेषताएं। तभी तो इसे 'ओमनी' (अंग्रेजी भाषा का शब्द जिसका अर्थ है 'सर्वांगीण') नाम दिया जाना स्वाभाविक ही था। आइए अब इसकी अन्य विशेषताओं पर गौर करें।

भीतरी-भाग: अनेक उपयोग

एक आम गणना के अनुसार ओमनी के भीतर का क्षेत्र 7.5 क्यूबिक मीटर होता है। पिछली सीट हटा दीजिए। लीजिए मारुति ओमनी सामान ले जाने वाली वैन, पिकनिक की गाड़ी या दूसरे शहर में जाने के लिए बड़ी कार के रूप में तैयार।

फिर भी आपके लिए यह फैमिली कार, ऑफ़िस कार, तथा शहर में दूर-सुदूर तक जाने वाली सुदृढ़ कार बनी रहती है।

वास्तव में, इसमें इतना अधिक स्थान होने की बदौलत आप इसका उपयोग जैसे कर सकते हैं।

मारुति ओमनी—चलाने में आराम

ओमनी चलाने का आनन्द ही कुछ और है। इंस्ट्रूमेन्ट पैनल सुन्दर और सुविधाजनक। स्टीयरिंग कॉलम की पोज़ीशन बिल्कुल सही। सीटों में फेर-बदल सम्भव। कन्ट्रोल लीवर तथा गियर शाफ्ट हाथ से छू लेने वाली दूरी पर।

और हाँ, सांस लेने के लिए भी बहुत खुला स्थान।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आज की सबसे खुली कार!

मारुति का अति कार्यशील सुज़ूकी इंजन

स्क्वेयर तौर पर 3 सिलेंडर, 4 स्ट्रोक, 800 सी सी का इंजन। अन्य शब्दों में यह है इंजन की श्रेष्ठ कार्यकुशलता और उच्च क्षमता वाला इंजन। इसे बिना-परेशानी 1,50,000 किलोमीटर तक आराम से चलाया जा सकता है। इसके बाद इसे 'री-बोर' भी किया जा सकता है।

मारुति की विशेषताएं

सुरक्षा और मज़बूती मारुति की अनिवार्य विशेषताएं हैं, जबकि महत्त्वपूर्ण बात यह है कि ऐसी खूबियां अधिक मंहगी कारों में पाई जाती हैं।

* एक स्वतंत्र मैक्फर्सन स्ट्रट सस्पेंशन–अगली तरफ़, तथा लीफ़-स्प्रिंग टाइप सस्पेंशन-पिछली तरफ़।
* 30 सेंटीमीटर व्यास के 'ड्राप-सेंटर' पहिए सुरक्षापूर्ण ढंग से घूमने और कम जगह में आसानी से मोड़ने की सुविधा प्रदान करते हैं।
* 'सिंक्रोमेश' फॉरवर्ड गियर तथा दोहरा ब्रेकिंग सर्किट।
* ज़ंग से पूरी तरह बचाव के लिए इलेक्ट्रोफ़ोरेटिक पेन्ट से उपचारित फ्रेमवर्क।
* इंजन ठंडा रखने की विशेष व्यवस्था, जिससे रोज़-रोज़ रेडियेटर में पानी भरने की मुश्किल दूर हो जाती है।

मारुति ओमनी: निःसंदेह एक उत्तम कार। उससे भी उत्तम बात है इसका सबसे खुली कार होना।

(डी.जी.एस. एण्ड डी रेट कॉन्ट्रेक्ट पर भी उपलब्ध)

चित्र में दर्शाया गया सहायक सजावटी/उपयोगी सामान ओमनी की बिक्री में शामिल नहीं।

MARUTI **OMNI** खुले आराम का सफ़र

मारुति उद्योग लिमिटेड 11 वीं मंजिल, जीवन प्रकाश, 25 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110 001

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तरुण और सविता के चेहरे पर झलकती मुस्कान का रहस्य!

वे प्रसन्न हैं क्योंकि उनकी मोपेड हार्ड क्रोम प्लेटिड बोर वाले अल्यूमीनियम सिलिन्डर से सुसज्जित होने के कारण अन्य किसी मोपेड की तुलना में अधिक टिकाऊ व कार्यकुशल है. हार्ड क्रोम प्लेटिड बोर वाले अल्यूमीनियम सिलिन्डर को लगभग 60,000 किलोमीटर चलने पर जबकि साधारण सिलिन्डर को लगभग 20,000 किलोमीटर चलने पर ही री-बोरिंग की आवश्यकता पड़ जाती है.

पेसर वन पीस ट्यूब्यूलर फ्रेम व 41 सै.मी. के पहियों के कारण शहर के यातायात के लिए अत्यन्त अनुकूल. पैन्थर ठोस वैल्डिड फ्रेम व 48 सै.मी. के पहियों के कारण उबड़-खाबड़ मार्ग के लिए एक आदर्श वाहन. अच्छी पिक-अप और पेट्रोल की बचत के लिए दोनों मोपेड दंतीली ट्रांसमिशन बेल्ट से सुसज्जित.

ये ऐसे वाहन हैं जो पेट्रोल की कम खपत में अत्याधिक शक्ति प्रदान करते हैं यही पेसर और पैन्थर की तकनीकी विशेषता है.

हार्ड क्रोम प्लेटिड बोर वाले अल्यूमीनियम सिलिन्डर से सुसज्जित होने के कारण 40,000 किलोमीटर अधिक चलने में सक्षम

पैन्थर पेसर

मैजेस्टिक ऑटो लिमिटेड

प्रस्तुतकर्ता हीरो-मैजेस्टिक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इंडिया टुडे
सूचना समाचार पत्रिका
वर्ष 2 अंक 9 1-15 मार्च, 1988
प्रधान संपादक: अरुण पुरी
वरिष्ठ संपादक: प्रभु चावला
लिविंग मीडिया इंडिया प्रा. लि., एफ-14, कपिटेंट हाउस, कनाट प्लेस, नई दिल्ली के लिए अरुण पुरी द्वारा संपादित और प्रकाशित तथा थामसन प्रेस इंडिया लि. फरीदाबाद, हरियाणा में मुद्रित.

संपादकीय कार्यालय:
लिविंग मीडिया इंडिया प्रा. लि., एफ-14/15, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001. फोन: 331 5801-4, टेलेक्स: 31-61245 INTO IN, तार: लिवमीडिया नई दिल्ली.

मुख्य सर्कुलेशन कार्यालय:
इंडिया टुडे सर्कुलेशन मैनेजर, एफ-14, कपिटेंट हाउस, कनाट प्लेस, मिडल सर्कल, नई दिल्ली-110001. फोन: 3313076-8, टेलेक्स: 31-62634 INTO IN, तार: सर्कुलेट, नई दिल्ली.

मुख्य विज्ञापन कार्यालय:
28 ए और बी, जॉली मेकर चैंबर-2, नरीमन पाइंट, बंबई-400021. फोन: 2026152, 2029326, 2029435, टेलेक्स: 11-5373 THOM IN, तार: लिवमीडिया बंबई.

क्षेत्रीय विज्ञापन कार्यालय:
के-9, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001, फोन: 352378, 323576, 351273, 351323; टेलेक्स: 31-62124 THOM IN, तार: लिवमीडिया, नई दिल्ली; फागुन चैंबर्स, 26 कमांडर-इन-चीफ रोड, मद्रास-600105. फोन: 477188, 477770, टेलेक्स: 041-6177 INTO IN, तार: लिवमीडिया, मद्रास; 74/1, मैट मार्क्स रोड, बंगलूर-560001. फोन: 568448, 579037, 579089, टेलेक्स: 0845-2217 INTO IN, तार: लिवमीडिया, बंगलूर; 12-सी, एवरेस्ट 46-सी, चौरंगी रोड, कलकत्ता-700016 फोन: 445398, 447726, टेलेक्स: 021-3138 INTO IN, तार: लिवइन-मीडिया, कलकत्ता.

कॉपीराइट 1984 लिविंग मीडिया इंडिया प्रा. लि. विश्व भर में सर्वाधिकार सुरक्षित. किसी भी रूप में सामग्री की नकल प्रतिबंधित. इंडिया टुडे अनिमंत्रित प्रकाशन सामग्री को लौटाने की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता.

नेपाल में 6 रुपए

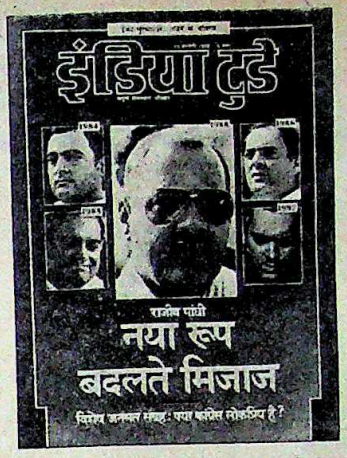

बदले-बदले-से सरकार...

आवरण कथा 'राजीव गांधी: नया रूप, बदलते मिजाज' (29 फरवरी '88) पढ़कर लगा कि 1988 का थुलथुल और गंजा राजीव 1984 के छरहरे राजीव से पूर्णतः भिन्न है. 1984 का राजीव 'मि. क्लीन' के नाम से जाना जाता था. लेकिन 1988 का राजीव एय्याश, चमचों से घिरा हुआ तथा 'नानी याद कराने वाला' है. वह कहता कुछ, करता कुछ और है.

—नलिन कुमार सिंह, मलहीपुर (बिहार)

■ राजीव गांधी ने जनता की भावनाओं तथा आशाओं के साथ एक गंदा खेल खेला है जैसे किसी भिखारी को महलों का ख्वाब दिखाकर नंगा करके दुलत्ती झाड़ दी जाए. आप कितना भी सर्वेक्षण कर लीजिए, अगले चुनाव में जनता की अदालत उन्हें 'राजनैतिक मौत' की सजा सुनाएगी.

—संजय श्रीवास्तव, इलाहाबाद (उ.प्र.)

■ आवरण कथा में जनमत संग्रह 'विकल्प की कमी' (29 फरवरी) पढ़ा. यदि विवादों से घिरी राजीव की पार्टी फिर लोकसभा में पूर्ण बहुमत हासिल कर लेती है तो यह भारतीय जनता और विपक्ष का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा. विपक्ष को शायद ही फिर ऐसा अवसर मिल पाए.

—जसबीर सिंह, चंडीगढ़

■ कथित मध्यावधि चुनावों में बिखरा, बंटा, उद्देश्यहीन विपक्ष मात्र 'राजीव विरोध' का रोना रोकर कुछ भी हासिल नहीं कर सकता.

—कंचननाथ माथुर, नयाबांस (राज.)

■ आपके इस जनमत सर्वेक्षण से विपक्ष का खोखलापन एक बार फिर उजागर हुआ है. विपक्ष को अगस्त वाले सर्वेक्षण से ही चेत जाना चाहिए था. परंतु उन्हें आपसी लड़ाई से मौका मिले तब न! लगता है कि अभागे भारतवासियों को यह बड़बोली और निकम्मी सरकार पांच साल और झेलनी होगी.

—नितिन कुमार, इलाहाबाद (उ.प्र.)

गुनाह किसका

'आजकल' स्तंभ में 'हरिजन होना गुनाह' (29 फरवरी) रिपोर्ट पढ़ी. दरअसल दुर्दशा के लिए स्वयं हरिजन और काफी हद तक सरकार भी जिम्मेदार है. मंदिर में पूजा का अधिकार तो वे सवर्णों की तरह चाहते हैं परंतु 'आरक्षण' का विरोध नहीं करते. तब वे हरिजन ही बने रहना चाहते हैं. सरकार भी एक ओर तो भेदभाव मिटाने का दम भरती है, दूसरी ओर आरक्षण द्वारा इसे खुद ही प्रोत्साहित करती है.

—कु. मनीषा अग्रवाल, ग्वालियर (म.प्र.)

■ लेख कट्टरवादी सवर्ण हिंदुओं की छिछली और निम्न मानसिकता को उजागर करता है. मुझे संदेह है कि हरिजनों को मंदिरों में प्रवेश न करने देने से उनका 'ईश्वर' ज्यादा प्रसन्न होगा.

—राजन चोपड़ा, नई दिल्ली.

शर्म तो समाज करे

'दहेज की बलि' (29 फरवरी) रिपोर्ट पढ़कर दुख हुआ कि अभी तक इस लाइलाज कुरीति से हमारे समाज को छुटकारा नहीं मिल पाया है. जहां 40,000 रु. से 80,000 रु. तक की पेशकश करने वालों का यह हाल है तो उन लोगों की बेटियों का क्या हाल होगा जिन्हें दो समय की रोटी भी मुश्किल से मिलती है.

—अमर एस. बनेर, लुधियाना (पंजाब)

■ पूनम, ममता और अलका ने समाज में व्याप्त दहेज के ठेकेदारों को नंगा कर दिया है. अपनी पुत्रियों के दुर्भाग्य पर साहु दंपती को शर्म महसूस करने की कतई आवश्यकता नहीं. शर्म तो उस समाज को आनी चाहिए जो उनके स्वेच्छा से अंतरजातीय विवाह करने पर उन्हें नोचने को दौड़ा आता.

—अनमोल सुरोलिया, रतलाम (म.प्र.)

किसानों की उपेक्षा नहीं

'कसौटी' (29 फरवरी) पढ़ा. आपने किसानों की समस्याओं का एकदम सटीक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आकलन किया है. उनकी समस्याओं की अनदेखी करना अब किसी भी सरकार के लिए हानिकारक सिद्ध होगा.

—मुकेश परीना गुप्ता, गाजियाबाद (उ.प्र.)

पर जगह कहां है

आवरण कथा 'तंदुरुस्ती की बढ़ती तमन्ना' (15 फरवरी) पढ़ी. सचमुच आजकल व्यायाम हर व्यक्ति की जरूरत बनता जा रहा है, लेकिन जगह तंगी के कारण इसमें बहुत रुकावटें हैं. सरकार को चाहिए कि वह कम खर्च वाली व्यायाम शालाएं खुलवाए.

—अनिल सहगल, लुधियाना (पंजाब)

■ इसमें संदेह नहीं कि यह लेख पढ़कर लोगों के मन में तंदुरुस्ती की इच्छा पैदा होगी. मेरा मन कर रहा है कि ट्रैक सूट पहनकर पार्क की ओर दौड़ पड़ूं. पर अफसोस, 22 जनवरी को बरनाला में हुए कांड को देखकर लगता है कि हम पंजाब-वासियों को खुले आम व्यायाम करने का कभी मौका ही नहीं मिलेगा.

—ज्ञानचंद्र शर्मा, मोगा (पंजाब)

■ सामग्री रुचिकर थी लेकिन इसका क्षेत्र महानगरों तक ही सीमित है. शहरों में व्यायाम की बढ़ती प्रवृत्ति को भी प्रदर्शित करना चाहिए था. एरोबिक्स जैसे व्यायाम केवल अभिजात्य वर्ग तक ही सीमित हैं. अधिकांश लोग तो दौड़ना, जॉगिंग, योगाभ्यास, दंड-बैठक जैसे फायदेमंद और मितव्ययी व्यायाम ही करते हैं.

—संजय मिश्र, छतरगढ़ (राज.)

आडंबरपूर्ण पद्धति

भारत में आजकल तंदुरुस्ती बढ़ाने की नई-नई विधियां इस्तेमाल में लाई जा रही हैं. आपने मोटे लोगों को तंदुरुस्त बनाने पर काफी लिखा लेकिन जिनका वजन पहले से ही कम है उन लोगों के लिए संतोषप्रद सामग्री आपने नहीं दी.

—कृष्णगोपाल तिवारी, इलाहाबाद (उ.प्र.)

■ लेख आडंबरपूर्ण है. इसका सबूत मुख-पृष्ठ का चित्र है जिसमें चारों युवाओं को कसरत की कम और अपने कपड़ों और कैमरे की ओर देखकर मुस्कराने की चिंता ज्यादा है. नए-नवेले स्वास्थ्य क्लब व रंगीन फोटो वाले लेखों, विज्ञापनों का एकमात्र उद्देश्य नर्सिंग होमों की तरह पैसा कमाना ही है. इन्हें जनता के स्वास्थ्य से कोई सरोकार नहीं. महंगे कपड़े और जूतों से लैस, संगीत पर उलटे सीधे हाथ-पांव चलाते ये दिग्भ्रमित युवा जिस स्वास्थ्य को प्राप्त करना चाहते हैं वह एक खतरनाक प्रवृत्ति है. आपका लेख इसे बढ़ावा देता है.

—डॉ. राजेंद्र कुमार, मुजफ्फरनगर (उ.प्र.)

यह एक अंकुश

कसौटी में 'सत्ता का सम्मोहन' पढ़ा. राजीव कहते हैं 'अखबार मत पढ़िए ये सरासर झूठ छापते हैं.' प्रेस जब तक राजीव की चापलूसी करे तो सिर आंखों पर और यदि सच लिखे तो झूठी. सच तो यह है कि प्रेस मदमस्त हाथी रूपी सत्ताधारी पर एक अंकुश है जो समय-समय पर उसे उसके कर्तव्य के प्रति सचेत करता रहता है.

—राजेश जैन, सागर (म.प्र.)

■ प्रधानमंत्री की प्रेस से चिढ़ साबित करती है कि वे कहीं कुछ छिपाए रखना चाहते हैं पर समाचारपत्र सब कुछ उगल रहे हैं और प्रधानमंत्री को यह नहीं सुहा रहा. बेहतर होगा प्रधानमंत्री अपने कारनामों से चिढ़ें.

—बुरहानुद्दीन शकरुवाला, इंदौर (म.प्र.)

■ वास्तव में सत्ता का मद आदमी को इतना मदहोश कर देता है कि उसे किसी भी तरह का भय नहीं रहता. पर यह मदहोशी अधिक समय तक टिकती नहीं. आखिरकार उसे जनता की अदालत में आना ही पड़ता है. शांति निकेतन के छात्रों को 'महत्वपूर्ण सलाह' देकर राजीव गांधी ने अपने शासन के ताबूत में एक कील और ठोंकी है. शायद वह भूल गए कि प्रेस की शक्ति ही वास्तव में जनता की शक्ति है.

—परमजीत सिंह, बरेली (उ.प्र.)

■ यह कितनी हास्यास्पद बात है कि शांति निकेतन के आचार्य होने के बावजूद राजीव गांधी ने छात्रों को सलाह दी कि अखबार मत पढ़िए, वे सरासर झूठ छापते हैं. सभी जानते हैं कि प्रेस लोकतंत्र का एक मुख्य स्तंभ है. राजीव को क्या हक है कि वे अपना बदला साधने के लिए छात्रों को ऐसी झूठी नसीहत दें?

—प्रमोद कुमार सिंह, कष्टहारा (बिहार)

■ राजीव तपे हुए, क्रमबद्ध सीढ़ी चढ़े हुए, जनता के बीच पनपे हुए राजनेता तो हैं नहीं. लोकतंत्र में प्रेस की भूमिका कितनी जरूरी है इससे वे बेखबर हैं. महात्मा गांधी और राजीव गांधी में यही फर्क है. राजीव तो राजपथ पर नजर रखकर कदम उठाने हैं. जनपथ तो उनके लिए सिर्फ साधन है, साध्य नहीं. इसलिए अगर वे प्रेस में छपे अक्षरों से परहेज रखने की सलाह देते हैं तो कोई आश्चर्य नहीं.

—निर्मलकुमार पाटोदी, इंदौर (म.प्र.)

आग तभी बुझेगी

'वर्दी वालों पर वज्रपात' (15 फरवरी) पढ़ा. इस शर्मनाक घटना से भारत की नारियों को जितनी लज्जा, अपमान, क्षोभ, घृणा और पीड़ा हुई है वह कहने योग्य नहीं है. पीड़ा और अपमान से धधकते कलेजे पर सेशन जज वी.डी. दुबे के निर्णय से कुछ ठंडे छींटे पड़े हैं, पर कलेजा ठंडा उसी दिन होगा जिस दिन इन नरभक्षियों को फांसी दी जाएगी. राजीव सरकार महिला कल्याण की बातें न करके महिला सुरक्षा विधेयक बनाए तो ज्यादा अच्छा होगा.

—रंजना श्रीवास्तव, आर्यनगर (उ.प्र.)

■ दुबे के महत्वपूर्ण फैसले की दाद देनी होगी जिन्होंने सजा सुनाकर उन पुलिसवालों का पर्दाफाश किया है जो खुद को लोगों का रक्षक बताते हैं. समाज को बचाए रखने के लिए ऐसे आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों का सफाया जरूरी है.

—चरनजीत सिंह सैनी, भोपाल (म.प्र.)

■ इस बहुचर्चित और बहुप्रतीक्षित फैसले के साथ ही शर्मनाक हत्या के काले अध्याय का सुखद अंत हो गया न्यायमूर्ति दुबे के इस फैसले ने भारतीय न्याय. व्यवस्था में आस्था और विश्वास का सुनहरा पृष्ठ जोड़ा है. यह फैसला पुलिस ही नहीं अपितु हर उस शख्स के लिए सबक है जो नारी की अस्मत को नीलाम करना अपनी शूरवीरता का परिचायक मानता है.

—हितेंद्र पवार, खंडवा (म.प्र.)

लोकतंत्र की अर्थी

'सिंहासन के लिए संघर्ष' (15 फरवरी) पढ़कर ऐसा लगा कि जब केंद्र सरकार ही कुर्सी के लिए इतना लड़-झगड़ रही है तो आम आदमी से क्या अपेक्षा की जा सकती है. जानकी और जयललिता की लड़ाई देखकर तो लगता है जैसे सदन न होकर कबड्डी का मैदान हो.

—संजीव धनशाला, बिजनौर (उ.प्र.)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

स्टायलिश इरा

ग्रेविरा

GRAVIERA SUITING GR®
A Quality Product of Grasim Industries Ltd.

Krishma/BTM/36/2720 HI

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

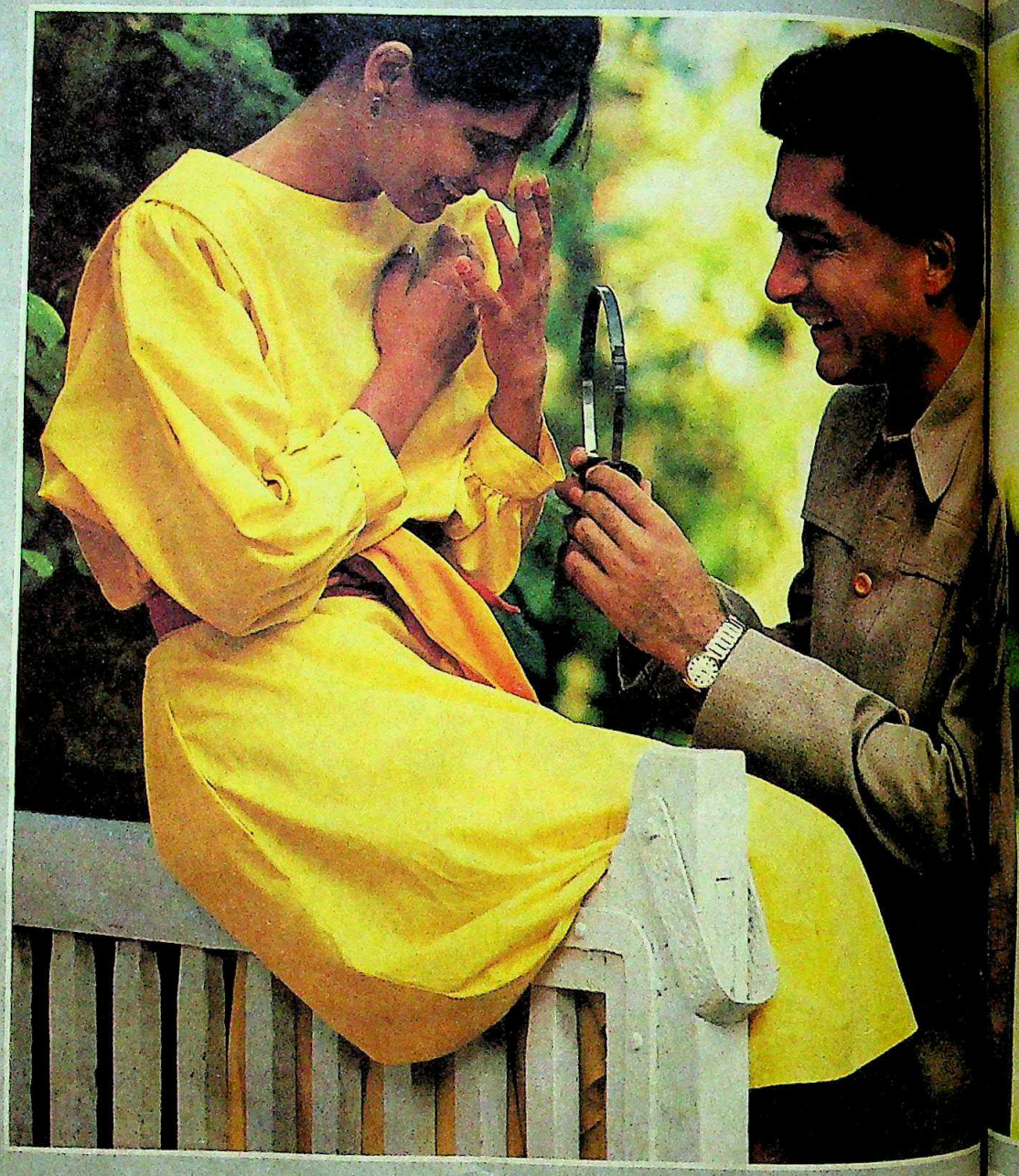

झिझकती आँखें झुकाये वह बोली, "घर के सि
बिस्मिल्ला खान के शहनाई वादन के साथ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"घर की ऐसी बात टेप पर नहीं बताते,
इन के साथ भी नहीं!"

स्प्रिंग फील्ड

जीवन के अनमोल क्षणों में **रेमण्ड**

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मज़ा आ गया

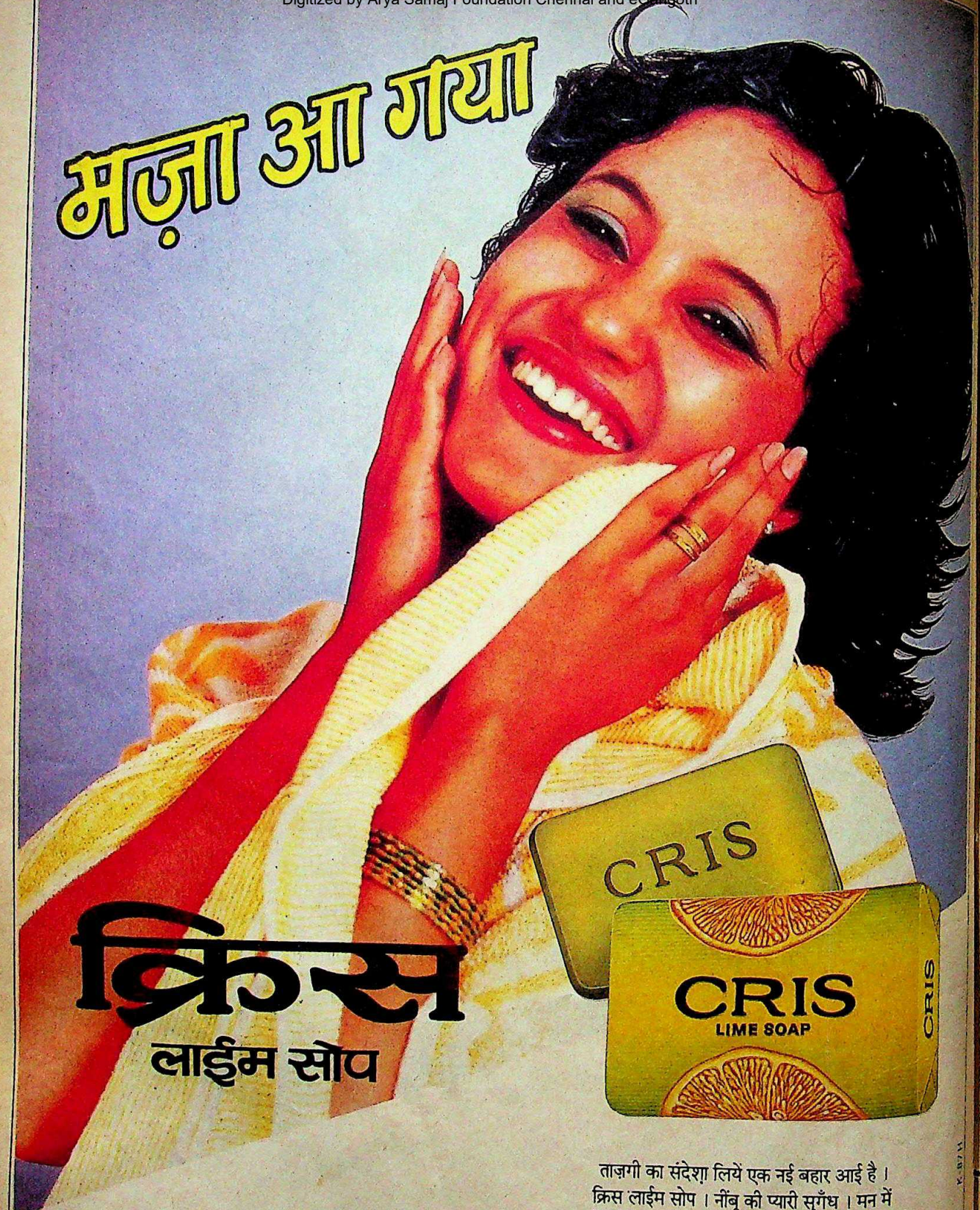

क्रिस
लाईम सोप

ताज़गी का संदेशा लियें एक नई बहार आई है।
क्रिस लाईम सोप। नींबू की प्यारी सुगँध। मन में
उभरती हुई खुशी। क्रिस लाईम सोप से नहा कर तो देखिये।
आप कह उठेंगे, 'मज़ा आ गया !'

नीबूं की महकती ताज़गी

A Kusum Product
विश्वास कें साथ खरीदियें

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

■ इंका तमिलनाडु में अपनी सरकार बनाने की बेहद इच्छुक है. विधानसभा में अशोभनीय व्यवहार और पुलिस द्वारा लाठी चार्ज ऐसी घटनाएं हैं जिन्होंने लोकतंत्र की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है.

—अमित कुमार, चंडीगढ़ (पंजाब)

■ जानकी सरकार को इंका द्वारा ऐन मौके पर अंगूठा दिखाने वाली बात कोई नई नहीं है. 1979 में इंका चरण सिंह के साथ भी ऐसा कर चुकी है. राजीव सरकार देश में सूखे से निबटने के बजाय घटिया राजनैतिक उठापटक में लगी है.

—देवेंद्र पाल सिंह राठौड़, चुरु (राज.)

सत्ता का खेल

'निकले बड़े बेआबरू होकर' (15 फरवरी) पढ़ा. एक योग्य, बहुमतप्राप्त तथा अनुभवी नेता को कुछ तुच्छ स्वार्थी तत्वों के आरोपों के कारण कुर्सी छोड़ने को मजबूर होना पड़ा. इससे राजस्थान में राजनैतिक अनिश्चितता ही बढ़ेगी.

—घनश्याम जोशी, तेजरासर (राज.)

■ लेख में वास्तविक स्थिति का प्रतिपादन किया गया है. नए नेता का चुनाव निर्वाचन की समस्त लोकतांत्रिक परंपराओं और मूल्यों को ताक पर रख कर 'केंद्रीय आदेश' के अनुसार किया गया है. ऐसे आदेश की पुनरावृत्ति मध्य प्रदेश तथा बिहार में भी देखने को मिली.

—केशरीनंदन जैन, जयपुर (राज.)

■ ऐसा लगता है कि आलाकमान जिस तरह चाहे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बदल सकता है. सत्तापक्ष का मुख्यमंत्री चाहे जैसे नचाया जाता है. इस तरह लोकतंत्र का गला दबाया जा रहा है.

—नरेंद्रप्रकाश शर्मा, रायसिंहनगर (राज.)

जायज फैसला

'सांच पर आंच' पढ़ा. बंबई हाईकोर्ट के न्यायाधीशों—बख्तावर लेंटिन और सुजाता मनोहर की खंडपीठ का 'तमस' के बारे में फैसला सर्वथा उचित है. तमस में दिखाए गए सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता. क्या ही अच्छा होता यदि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दूरदर्शन पर दिखाए जा रहे भौंडे विज्ञापनों और सिनेमाघरों में अश्लील फिल्में दिखाने पर पाबंदी लगाने की मांग करते.

—प्रवीण रंजन सिंह, इलाहाबाद (उ.प्र.)

कानून का कायदा ताक पर

'अंधियारा फिर घिर आया' (15 फरवरी) पढ़ा. आज उग्रवादी जिस तरह निरंकुश और बेखौफ होकर बेगुनाह लोगों का कत्ल कर रहे हैं उससे यही साबित होता है कि उग्रवादी अपने उद्देश्य में सफल रहे हैं और कानून-व्यवस्था मजाक भर रह गई है.

—प्रणय कुमार मिश्र, जमालपुर (बिहार)

■ लेख पढ़कर मन सिहर उठा. आतंकवादी लोगों को मारते रहेंगे, और हमारी सरकार सिर्फ 'देखना है, देखेंगे' भर कहती रहेगी.

—मुरलीधर बाटवानी, धुलिया (महाराष्ट्र)

■ लगा कि सरकार की आतंकवाद विरोधी मुहिम शिथिल पड़ गई है. पंजाब में हो रही नृशंस हत्याओं के बारे में पुलिस महानिदेशक जे.एफ. रिबेरो का बयान कि इन हत्याओं में आतंकवादियों द्वारा कोई एक निश्चित तरीका अख्तियार नहीं किया गया, पंजाब पुलिस की सक्रियता पर प्रश्नचिह्न है.

—मदनसिंह पवार, राजगढ़ (म.प्र.)

यदि आपका जन्म १९६३ से पहले हुआ है तो इस विज्ञापन को ध्यान से पढ़िए

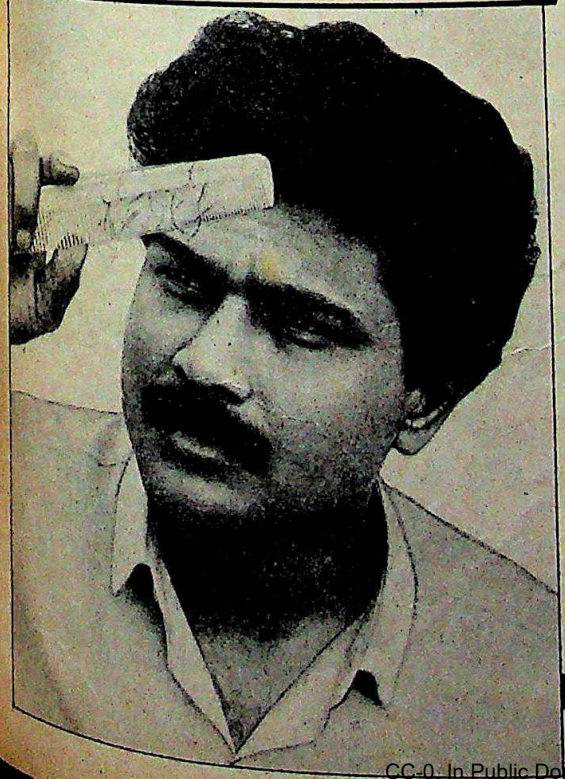

२५ साल से अधिक उम्र वाले १० में से ९ लोगों के बाल झड़ रहे हैं....लेकिन उन्हें इसका पता नहीं!

क्या आप उन ९ लोगों में से एक हैं? तब तो आज ही यह परीक्षण कीजिए

अपने बालों को ज़ोरों से कंघी कीजिए. अगर कंघी पर बाल उतर आएं तो समझ लीजिए आपके बाल झड़ रहे हैं.

इसका हल है — प्योर सिल्विक्रिन

बालों के झड़ने का कारण है —ज़रूरी अमिनो एसिड्स की कमी — जो आपके बालों की कुदरती खुराक है. केवल प्योर सिल्विक्रिन में ही वैज्ञानिक अनुसंधान से बना वह फार्मूला है जो इस कमी को पूरा करता है.

इसके कारण है :

१. प्योर सिल्विक्रिन १७ अमिनो एसिड्स का अनोखा मिश्रण है — आपके बालों की कुदरती खुराक.

२. नोबेल पुरस्कार विजेता अनुसंधान तकनीक यह प्रमाणित करती है कि प्योर सिल्विक्रिन बालों की जड़ों तक बहुत जल्दी पहुँचता है, बालों में कुदरती खुराक की कमी पूरी करता है और बालों को फिर से स्वस्थ बनाता है.

उत्तम परिणाम के लिए प्योर सिल्विक्रिन को सर की त्वचा पर तब तक प्रतिदिन दो बार मलिए जब तक आपके बालों का स्वास्थ्य सामान्य नहीं हो जाता.

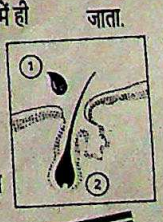

प्योर सिल्विक्रिन असरदार है — नोबेल पुरस्कार विजेता अनुसंधान तकनीक का प्रमाण.

प्योर सिल्विक्रिन

OBM/571/HIN M

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"३ कमाल वाला टूथपेस्ट क्यों हमने भी अपनाया"

"मानिए या ना मानिए, पर मैंने तो सचमुच अपना टूथपेस्ट बदल डाला है! अब मैंने अपनाया है **लौंग, फ्लोराइड** और **मिन्ट** के ३ कमाल वाला प्रूडेन्ट. है मेल इतना अच्छा, मानों दांतों का साथी सबसे सच्चा!
अनुराधा ने एक और खूबी पायी – प्रूडेन्ट की सॉफ्ट-स्क्वीज़ ट्यूब! सदा रहे साफ-सुथरी. ऐसी खूबी और किसी टूथपेस्ट में कहां है!"

मुफ्त! दांतों की देखभाल के लिए रंगीन पुस्तिका. सीमित संख्या में.
लिखिए : पारले प्रॉडक्ट्स प्रा. लि., निर्लोन हाउस, २५४-बी, डॉ. ए.बी. रोड, बम्बई ४०० ०२५.

प्रूडेन्ट में हैं कमाल ३, दांतों के लिए बेहतरीन

पारले

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कसौटी

असंतोष का आतंक

महात्मा गांधी ने 1915 में भारत में अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू करते हुए कहा था कि यह सत्य के उनके प्रयोगों की ही एक कड़ी है. आजादी की लंबी लड़ाई के लिए अपनी और राष्ट्र की संकल्प शक्ति को मजबूती प्रदान करने का, एक अजेय ताकत से अहिंसक राजनैतिक संघर्ष की रणनीति तैयार करने का यह एक अप्रतिम प्रयास था. और इस प्रयास से उभरा था जन विरोध का एक अनूठा स्वरूप, राजनैतिक संघर्ष का एक बिलकुल नया अस्त्र. इसके अपने कारण और गांधी के दृढ़ नैतिक बल के चलते जो कुछ भी हुआ उसकी कार्यविधि, उसकी तार्किकता असाधारण थी. वास्तव में इन्हीं सबके चलते जो रक्तहीन क्रांति हुई, जो आजादी मिली वह अपने आप में अपूर्व थी.

लेकिन आज देश उन सबको बहुत पीछे छोड़ आया है. एक शहर में पुलिस की बदतमीजी के विरोध में देश भर के वकील पूरी न्यायिक व्यवस्था को झकझोर कर रख देते हैं. राजधानी का व्यापारी वर्ग अपनी दुकानें बंद कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि संसद ने जो टैक्स कानून पास किया है वह उसके लिए नुकसादेह है. और नाराज किसान हफ्तों तक एक शहर की घेराबंदी कर देते हैं वह भी बिजली बिल माफ करने की ऐसी मांग पर जिसे शायद ही कोई सरकार मानने को तैयार हो. अगामी हफ्तों में ऐसे और उदाहरण सामने आएंगे— दिल्ली में विरोध रैलियों का आयोजन, महंगाई के खिलाफ मजदूर संघों की देशव्यापी हड़ताल, बोफोर्स से लेकर फेयरफैक्स जैसे मुद्दों पर विपक्षी दलों का भारत बंद आह्वान आदि-आदि.

रेखाचित्र: अजीत नाइनन

भारत ही शायद दुनिया में एक अकेला देश है जहां विरोध प्रदर्शन के लिए न केवल सार्वजनिक गंदगी फैलाई जाती है बल्कि सामान्य जनजीवन का भी कोई ख्याल नहीं रखा जाता. आजादी की लड़ाई के दौरान बंद, हड़ताल, असहयोग (मसलन टैक्स न देना), जन प्रदर्शन आदि को जो मान्यता मिली उसका आज बेहद मनमाने तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, भले ही स्थितियां या मुद्दे इनके उपयुक्त हों या नहीं या विरोध प्रदर्शन के दूसरे कम नुकसानदेह तरीके उपलब्ध हों या नहीं.

अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब लापरवाह किस्म के युवक और छात्र बात-बात पर अफरातफरी मचा देते थे, भाड़ा बढ़ाए जाने पर बसें फूंकने लगते थे. लेकिन आज स्थिति यह है कि लगता है समाज के सम्मानित और रूढ़िवादी तबके भी विरोध के वे तौर-तरीके अपनाने में कतई हिचक नहीं रहे जिन्हें कुछ वर्षों पूर्व तक वर्जनीय माना जाता रहा. छोटे-छोटे मसले पर भी इतना व्यापक और उग्र विरोध होता है जो मसले के महत्व के अनुपात में कुछ ज्यादा ही होता है.

यह सब और कुछ नहीं, सत्य के बगैर सत्याग्रह ही है. मानो अहिंसक विरोध समाज के साथ हिंसा कर रहा हो. वकीलों का अगर पुलिस से झगड़ा है तो रहे, न्याय के लिए न्यायालय के दरवाजे पर आने वालों को न्याय मिलने में देरी क्यों हो? संसद के किसी कानून का विरोध क्या हर जगह दुकानें बंद करके ही हो सकता है? और कोई रास्ता नहीं? और किसानों की आर्थिक मांगें जायज भले हों लेकिन क्या इसके लिए सरकारी दफ्तरों की घेराबंदी उचित है समाज के जिम्मेदार तबके जब इस तरह के अतिवादी तरीके अपनाने लगें तो पूरी व्यवस्था से संबंधित ये मौलिक प्रश्न लाजिमी तौर पर उठते हैं.

यह सही है कि शिकायतों और समस्याओं के प्रति पूरी व्यवस्था का रवैया कुल मिलाकर संतोषजनक नहीं है, कि जब तक पानी सिर पर से गुजरने नहीं लगता या कोई खास तबका अपनी ताकत का पूरा एहसास नहीं कराने लगता तब तक सरकार भी आंखें मूंदे रहती है. यानी इस बात की सख्त जरूरत है कि फैसले लेने वाले जो लोग हैं वे विरोध या असंतोष का समाधान करने के लिए तत्काल कार्रवाई किया करें क्योंकि असंतोष को नियंत्रण में रखने का यही उपयुक्त तरीका है. समाज के आम तौर पर अनुशासित माने जाने वाले तबके आज अगर उग्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो इसका कारण यही है कि उक्त तरीके आजमाए ही नहीं गए. पिछले कुछ हफ्तों ने साफ कर दिया है कि व्यवस्था वक्त पर कार्रवाई करने में नाकाम रही है, कि वह बुरी तरह भ्रष्ट और अपराध प्रेरक हो गई है. जब निहत्थे वकीलों पर भाड़े के गुंडे हमला करते हैं तो पुलिसवाले मामले दर्ज करने से मना कर देते हैं. उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के किसानों की समस्याओं पर समय रहते पर्याप्त ध्यान न देने की दोषी पाई जाती है. और हड़बड़ी में तैयार किया गया दोषपूर्ण कानून भी संसद में बहुमत के बल पर पास करा लिया जाता है. यह सुनने की जहमत भी नहीं उठाई जाती कि उस कानून की खामियां क्या बताई जा रही हैं.

किसी मसले के प्रति पर्याप्त ध्यान न देने के कारण विरोध भड़क उठता है तो अधिकारी अकसर दबाव के आगे झुक जाते हैं और एक तरह से विरोध को जायज ही करार ठहरा देते हैं. दिल्ली के वकील न्यायिक जांच की मांग कर रहे थे और उनकी मांग मान ली गई. पंजाब, गोरखालैंड या असम के मसले कुछ-कुछ इसी तरह के हैं— शुरू में जब हल्की लहर उठी तो कोई ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन एकबारगी जब विरोध उग्र हो उठा और आतंकवादी तेवर ने मसले को और ही रंगत दे दी तो रियायतें भी बढ़-चढ़कर दी गईं. जब हर आदमी गला फाड़ कर चिल्ला रहा हो तो दूसरों को भी लगता है कि उसकी आवाज तभी सुनी जाएगी जब वे भी उसी तरह चिल्लाएं. और इस शोरशराबे में अजब नहीं कि विवेक के स्वर दब कर रह जाएं.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रंगे हाथों पकड़ लिया ना!
पर, आपको अपने बचपन की वो
घड़ी याद है, बरसों पुरानी?

ज़रा याद कीजिए वो ज़माना ... बचपन में कहानियाँ पढ़ना-पढ़ाना.
क्या हसीन घड़ियाँ थीं वे. वे ही घडियाँ आज भी हैं.

जी हाँ, कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती.
जैसे कि ४५० लाख लोगों की ये हमसफर
घड़ियाँ. साथ दें ... हर पल, हर घड़ी.

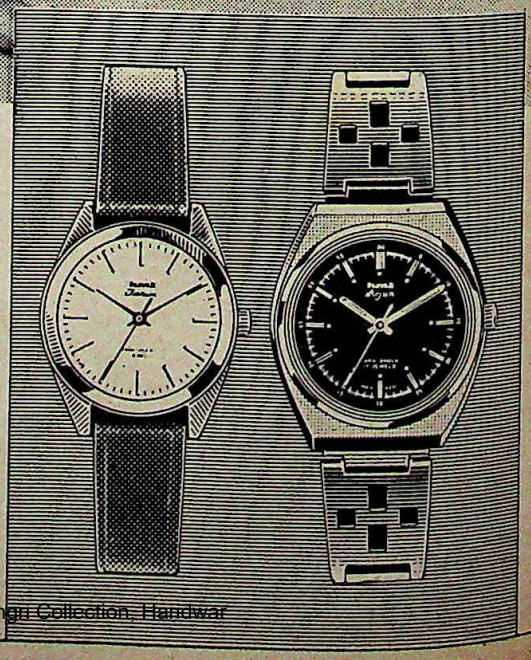

hmt
घड़ियां
राष्ट्र के समय प्रहरी

State's-1493/88 Hin

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शहंशाही करामात

● हिंदुस्तान में अमिताभ बच्चन होने के महत्व का जैसा प्रदर्शन पिछले पखवाड़े 'शहंशाह' रिलीज़ होने के दिन हुआ वैसे इससे पहले कभी नहीं हुआ था. लग रहा था कानो पूरी सरकारी मशीनरी एक फिल्म स्टार के आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए तैनात कर दी

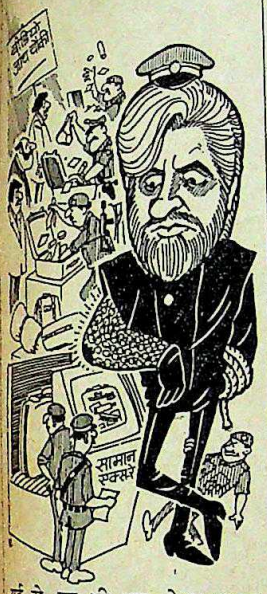

गई हो. वह भी एक ऐसा स्टार जिससे सुरक्षित दूरी बनाए रखने की आम राय के बावजूद राजीव गांधी उससे चिपके हुए हैं. अफवाह उड़ी कि फिल्म के वीडियो कैसेट बनाकर बड़े पैमाने पर उनका वितरण किया जाएगा. बस हुक्म के गुलाम अफसरों की फौज मैदान में कूद पड़ी ताकि ऐसे वीडियो चोरों को धर दबोचा जाए.

दिल्ली हवाई अड्डे पर भोपाल, वाराणसी, इंदौर और लखनऊ के लिए उड़ान भरने वाले यात्री यह देखकर दंग रह गए कि लगभग 50 पुलिस अधिकारी उनके सामान की जांच के लिए वहां पहले से मुस्तैद हैं. यह देखने के लिए कि कहीं कोई यात्री अपने साथ 'शहंशाह' की वीडियो कॉपी तो नहीं ले जा रहा. हर यात्री के हाथ वाले और दूसरे सामान की बारीकी से जांच की गई. यहां तक कि एक्स-रे मशीन के परदे पर कैसेट से मिलती-जुलती चीज़ दिखाई देते ही उस सूटकेस को खोलकर एक-एक चीज की जांच की गई. लेकिन बेचारे जांच अधिकारियों के हाथ कुछ भी नहीं लगा. पर यह बात तो समझ आ ही गई कि लक्षद्वीप में प्रधानमंत्री के साथ छुट्टियां मना लेने का पुण्य लंबे समय तक अपना असर बनाए रखता है.

चिट्ठी के मारे

● जैल सिंह राष्ट्रपति पद से भले ही रिटायर हो चुके हैं पर अभी भी वे राजीव गांधी सरकार के लिए आए दिन कोई न कोई नया सिरदर्द पैदा करते चले आ रहे हैं. लोग जानते हैं कि इन दिनों वे अपने संस्मरण लिखने में लगे हुए हैं. इसी सिलसिले में अब उन्होंने नए राष्ट्रपति आर. वेंकटरामन से एक अजीब आग्रह कर डाला है. पत्र लिखकर उन्होंने राष्ट्रपति से कुछ फाइलें दिखाने का आग्रह किया है. इनमें से कई फाइलें उनके दौर में घटी विवादास्पद घटनाओं से जुड़ी हैं और 'गोपनीय' श्रेणी में आती हैं. अपने पूर्ववर्ती के इस आग्रह पर असमंजस में फंसे राष्ट्रपति ने तुरंत ही यह पत्र गृह मंत्रालय को भेज दिया. वहां के अफसरों ने अपने सिर से बला टालने के लिए यह पत्र खुफिया ब्यूरो को भेज दिया. वहां भी बिना अधिक समय लगाए इसे कानून मंत्रालय की झोली में डाल दिया गया, जहां इस पर फिलहाल

सभी कार्टून: अजीत नाइनन

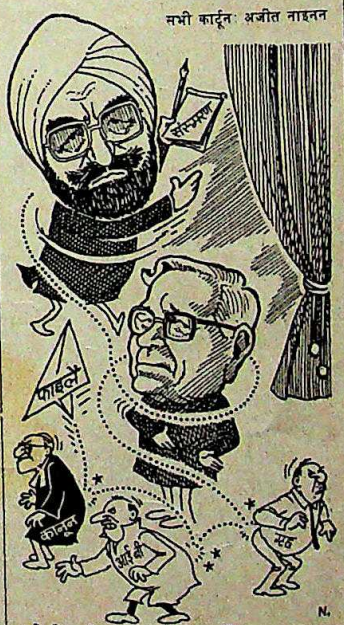

कोई फैसला नहीं हो पा रहा. जानकार लोगों का कहना है कि ज्ञानी जी की रुचि किसी सरकारी भेद को सार्वजनिक करने में नहीं है. इन फाइलों को देखने के पीछे उनका इरादा अपने राष्ट्रपति काल में घटी कुछ नाजुक घटनाओं की याद ताजा करना भर है.

सूची का चक्कर

● कहा जाता है कि कि सत्ता का असली केंद्र सूचनाएं होती हैं. इन्हें हाथ से निकलने देने का मतलब है हाथ से ताकत निकलने देना. इस नियम का पालन जिस लगन के साथ हमारे अफसरशाह करते हैं, उतना कोई और नहीं करता. यहां तक कि प्रधानमंत्री के सहयोगियों

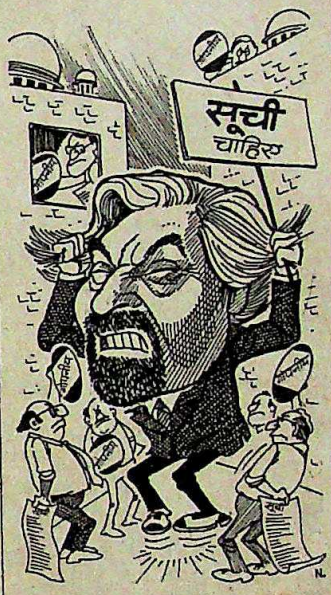

को भी अपने सरकारी विभागों से आंकड़े इकट्ठे करने में छठी का दूध याद आ जाता है. इस बात का एहसास हाल ही में राजीव के चहेते सैम पित्रोदा को तब हुआ जब उन्हें देश में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं की पूरी सूची की जरूरत पड़ी. पित्रोदा ऐसे कई तकनीकी कार्यक्रमों की अध्यक्षता कर रहे हैं जिनका गठन ग्रामीण समस्याओं को समाप्त करने के लिए किया गया है. कई गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं की सेवाएं इन कार्यक्रमों के लिए वे पहले ही ले चुके हैं.

लेकिन सूची पूरी उपलब्ध न होने के कारण राष्ट्रीय स्तर पर इन संस्थाओं को कंप्यूटरबद्ध करने और उन्हें कार्यक्रमों में शामिल किए जाने की पित्रोदा की योजना रास्ते में ही अटकी पड़ी है. ऐसा नहीं है कि यह जानकारी उपलब्ध नहीं है. दरअसल एक सूची गृह मंत्रालय के पास है और शेष संस्थाओं की सूची मानव संसाधन मंत्रालय के पास है. लेकिन दोनों मंत्रालयों ने इन सूचियों को 'गोपनीय' श्रेणी में रख छोड़ा है. उधर पित्रोदा भी अड़ गए हैं कि वे न केवल सूचियां प्राप्त करेंगे बल्कि उन्हें प्रकाशित भी करेंगे. फिलहाल तो यह मामला वहीं का वहीं अटका हुआ है.

समाजवादी उलझन

● समाजवाद के बारे में आए दिन प्रधानमंत्री के बदलते रवैये ने योजना आयोग तथा विभिन्न आर्थिक मंत्रालयों के अधिकारियों को असमंजस में डाला हुआ है. राजीव के नजदीकी अधिकारियों का कहना है कि प्रधानमंत्री आर्थिक व्यावहारिकता और जवाबदेही वाली अपनी नीति पर अभी भी टिके हुए हैं और वे जल्दी ही सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक जवाबदेह बनाने के लिए कुछ सख्त कदम भी उठाने जा रहे हैं.

प्रधानमंत्री सचिवालय के सूत्रों का कहना है कि 65 हजार करोड़ रुपए वाले विशालकाय सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में राजीव का नजरिया अब अधिक स्पष्ट होता जा रहा है. जिन प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है उनमें भिलाई इस्पात कारखाने जैसे उद्योग में जबरन रिटायरमेंट योजनाएं लागू करना, फालतू कर्मचारियों को एकमुश्त फायदे देकर 'अलविदा' कहना, और

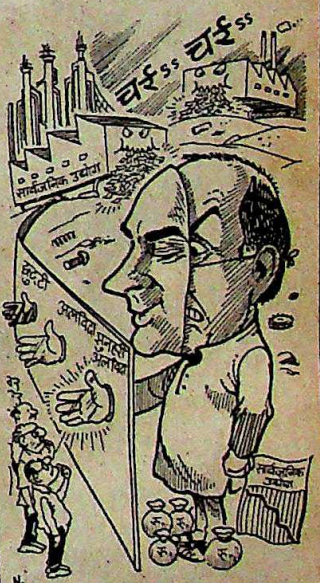

प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना भी शामिल है. वैसे तो इससे पहले भी कई बार इस तरह की योजनाओं पर बहुत चर्चा हो चुकी है पर प्रधानमंत्री के सहयोगियों का कहना है कि इस बार 'प्रधानमंत्री सचमुच गंभीरता से सोच रहे हैं और कुछ करने जा रहे हैं'.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सिर्फ एक बूटीमार के उत्पादन में 70 करोड़ रु. की लागत सार्थक रही!

इसकी फसल में
20% की बढ़ोतरी हुई.

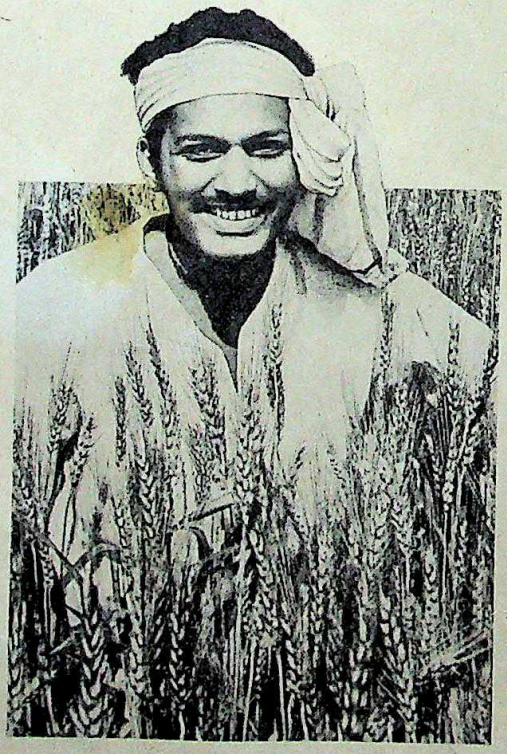

हॅक्स्ट को फसल की ज्यादा उपज की लगातार चिंता है. और इलाज की खोज चलती ही रहती है. कभी-कभी तो एक फसल-रक्षक दवा खोजने में 10,000 से 15,000 सम्मिश्रणों को परखा जाता है. इस काम में 10 से 12 साल तक लग जाते हैं-प्रथम रसायन-मिश्रण से लेकर उत्पादन के पंजीकरण तक. साथ ही असीम साधनों की लागत.

लेकिन, भारत में कहीं-न-कहीं, कीड़ों से फसल की रक्षा निश्चित है. पूरी की पूरी फसल बच जाती है. और हॅक्स्ट खेती-रसायनों से, हरएक बचाई या फूली-फली फसल, इस पूरे प्रयत्न को सार्थक बनाती है.

आज, हॅक्स्ट द्वारा निर्मित बूटीमार, गेहूं और धान की फसलों को हानिकर बूटियों से बचाने में मदद करते हैं. ताकि ये फसलें बचें और विकसित हों.

हॅक्स्ट के कीटनाशक, फफूंदनाशक और बूटीमार उत्पादन भी 20% तक बढ़ाते हैं.

साथ ही धान, कपास, दाल और तेल-बीज की फसलों को कीड़ों, बूटियों और बीमारियों से रहित वातावरण मिलता है.

हॅक्स्ट, पौधों, पशुओं और मनुष्यों का जीवन-स्तर ऊपर उठाने के लिए वचनबद्ध हैं. लगातार खोजबीन से, खेती-रसायनों, पशु-चिकित्सा उत्पादनों और औषध-रसायनों के विकास से जैव को सुरक्षित और विकसित करने के लिए. किसानों को कीट-प्रबंध की सलाह दे कर. ज्यादा उपज के लिए, उन्हें मिट्टी और जल-प्रबंध की जानकारी दे कर. और भारत में, हर संभव दृष्टि से जीवन-स्तर ऊपर उठाकर.

हॅक्स्ट इण्डिया
कृषि-रसायनों के निर्माता

क्योंकि जीवन मूल्यवान है

Hoechst

ULKA-HI-1-89

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

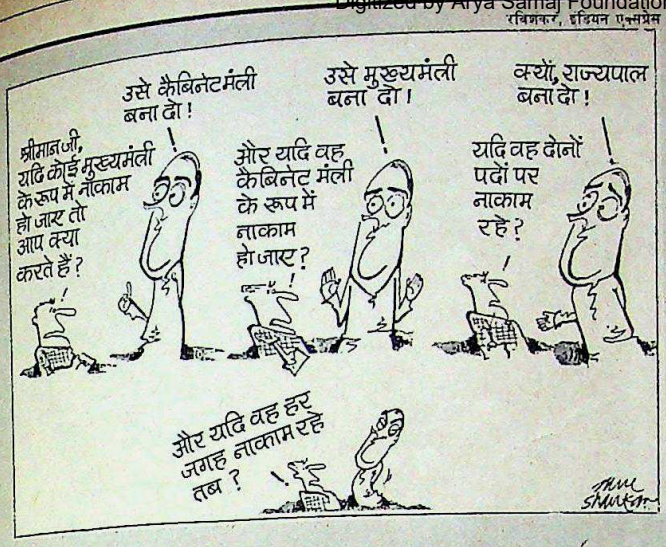

• पंजाब समस्या का समाधान फिलहाल भाग्य पर निर्भर है.
■ **राजीव गांधी,** *टाइम्स ऑफ इंडिया, दिल्ली*

• कितना अच्छा हो कि राजीव सिर्फ पंजाब को नहीं बल्कि पूरे देश को ही भाग्य के भरोसे छोड़कर एक तरफ हट जाएं.
■ **प्रो. दर्शन सिंह रागी,** *पंजाब केसरी, दिल्ली*

• हम राम जन्मभूमि का मसला एक घंटे में और पंजाब समस्या दो घंटे में हल कर सकते हैं.
■ **महेंद्र सिंह टिकैत,** *हिंदुस्तान, दिल्ली*

• मैं जानना चाहूंगा कि किस जगह और कहां मैं गलत साबित हुआ.
■ **मोतीलाल वोरा,** *मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे से ठीक पहले, दिनमान*

• हमें भ्रष्टाचारी और खराब छवि वाले कांग्रेसियों से मुक्ति पा लेनी चाहिए.
■ **राजीव गांधी,** *इंडियन एक्सप्रेस, दिल्ली*

• राज्य की कोई योजना समय से पहले धराशायी हुई तो उसमें लगे अभियंताओं और दूसरे अफसरों की टांगें तोड़ दी जाएंगी.
■ **भागवत झा आजाद,** (मुख्यमंत्री, बिहार) *हिंदुस्तान, पटना*

• ना बाबा ना! प्रधानमंत्री बनने की बात सोचना भी पाप है.
■ **नारायण दत्त तिवारी,** *दिनमान*

• राजीव तो कंप्यूटर युग में जा रहे हैं पर तमिलनाडु के कुछ इंका नेता अभी भी पाषाण युग में जी रहे हैं.
■ **पी.एच. पांडियन,** *इंडियन एक्सप्रेस*

• संविधान निर्माताओं ने सपने में भी न सोचा होगा कि कभी टैक्स लगाने के लिए भी अध्यादेश जारी किए जाएंगे.
■ **लालकृष्ण आडवाणी,** *जेटलमैन*

• राजनैतिक अभिनेता (वी.पी. सिंह) के मुकाबले 'शहंशाह' इलाहाबाद में कभी भी जीत सकते हैं.
■ **गुलाम नबी आजाद,** *टाइम्स ऑफ इंडिया*

• मैं तो खेलना चाहता हूं पर मेरी टांगें नहीं.
■ **विश्वनाथ,** *जनसत्ता*

• लोगों ने मुझे यह 'कर्नल' या 'मेजर' पता नहीं क्यों बना रखा है.
■ **दिलीप वेंगसरकर,** *पंजाब केसरी*

• लोग (सीता मानकर) मेरे पांव छूते हैं तो मैं शर्म से लाल हो जाती हूं.
■ **दीपिका,** *टीवी-वीडियो वर्ल्ड*

भरिए

यह कूपन और अपनी चहेती आवाज़ सुनिए: बच्चे की खिलखिलाहट

हंसी-खुशी और मौज-मस्ती बच्चों के लिए उतनी ही ज़रुरी हैं जितने ज़रुरी हैं खाना-पीना और हवा. और डिस्नी टुडे लेकर आया है यही मस्ती... यही मज़े.
बस तो फिर यह कूपन भर दीजिए और हर एक को खुश कर दीजिए.

आकर्षक छूट का लाभ उठाईये.

कूपन निम्नलिखित पते पर भेजें:
लिविंग मीडिया इंडिया (प्रा.) लि.
सबस्क्रिपशन डिपार्टमेंट
थॉमसन प्रेस बिल्डिंग
पो.बॉ. न० 69, दिल्ली-मथुरा रोड
फ़रीदाबाद - 121 007 (फ़रीदाबाद)

मुझे अपने बच्चे के लिए सबस्क्रिपशन चाहिए. यह रहा मेरा सालाना सबस्क्रिपशन ☐ हिंदी रु. 78/- ☐ अंग्रेजी रु. 96/- प्रति के लिए. मैं भुगतान चैक/मनी आर्डर/डिमांड ड्राफ्ट नं. _____ द्वारा कर रहा हूँ.

कृपया प्रति निम्नलिखित नाम व पते पर भेजें:
नाम _____
उम्र _____ लिंग _____
डाक-पता _____
_____
_____
विद्यालय : _____
माता-पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर _____

कृपया भुगतान लिबिंग मीडिया इंडिया (प्रा०) लि० के नाम पर बनाएं.

Walt Disney's डिस्नी टुडे
अब उपलब्ध हर पखवाड़े हिन्दी और अंग्रेज़ी में

© 1987 THE WALT DISNEY CO., USA.

MILESTONES/DT/114 Hin a

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गीयर्स औरों से ज़्यादा

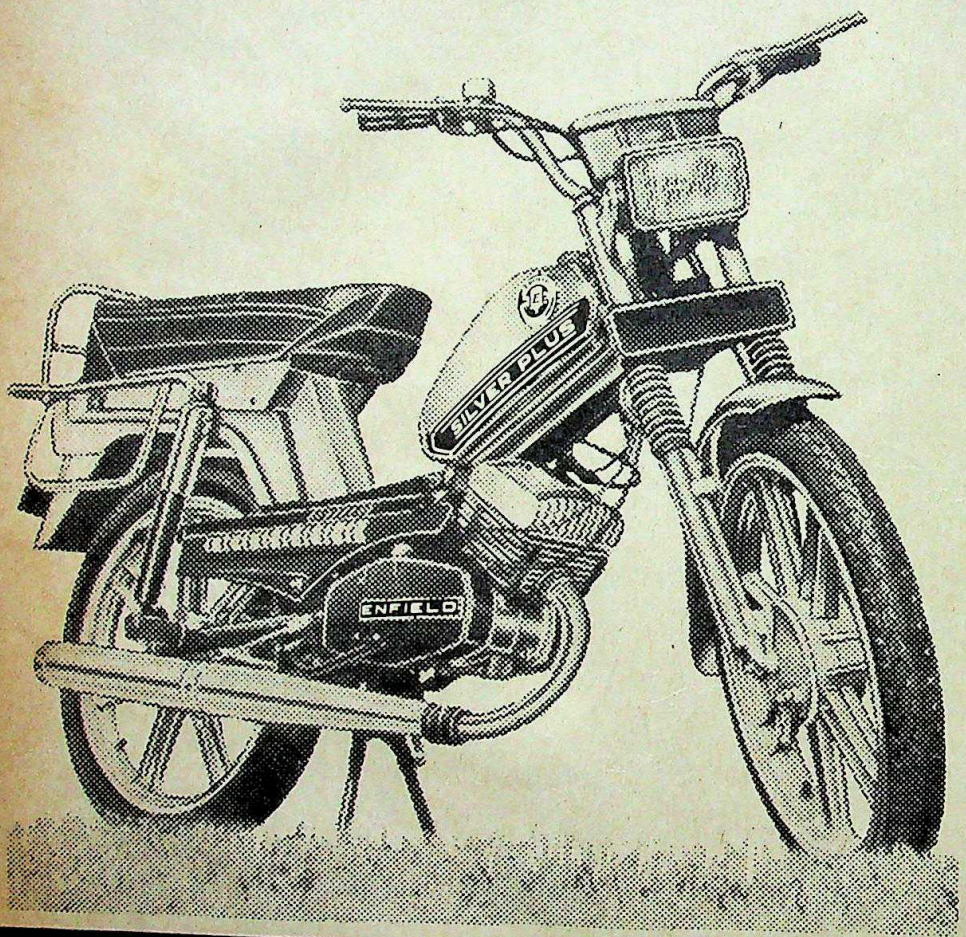

सिल्वर प्लस
एक विशिष्ट बाइक
इसका एक-एक गुण और लक्षण सिल्वर प्लस को अन्य मोपेडों से कहीं अलग प्रतिष्ठित करता है।

- अधिक इंधन बचत और स्मूद ट्रॅन्समिशन (सुगम संचरण) के लिए टिवन केबल सिस्टम के साथ तीन गीयर।
- किक स्टार्टर। पेडल करने या धक्का देने की जरूरत नहीं।
- सुरक्षित सवारी और तुरन्त रोकने के लिए १२० मि.मी. डायामीटर के ब्रेक ड्रम।
- दो के लिए बड़ी व आरामदेह गद्दी।
- मज़बूत और टिकाऊ प्रेशर डाईकास्ट एल्युमिनियम के पहिए।
- मज़बूत और टिकाऊ हेवी ड्यूटी सुदृढ़ ढांचा।
- तेज़ पिक-अप और ६० कि.मी. प्रति घंटे की अधिकतम गति वाला ५० सीसी का २.८ बी एच पी इंजन
- इंजन को दीर्घायु प्रदान करने के लिए हाई क्रोम प्लेट एल्युमिनियम बैरल।
- ७० कि.मी. प्रति लीटर इसको किफायती बनाता है।
- बिना झटके की सवारी के लिए ६० मि.मी. स्ट्रोक वाला हाइड्रॉलिक सस्पेन्शन व स्विंग आर्म द्वारा बिठाया गया पिछला शॉक एबसॉर्बर।
- अधिक स्थिरता के लिए ६५ कि.मी. स्ट्रोक वाला आगे का टेलिस्कोपिक फोर्क।
- जर्मन तकनीक और एनफील्ड की निपुणता सिल्वर प्लस को एक विशेष अनुभव बना देती है।
- कई रंगों में उपलब्ध।

सिल्वर प्लस

असली टू-सीटर

ENFIELD

ऐसी सवारी जब मिले. महज मोपेड से काम न चले.

हमेशा एनफ़ील्ड के अतिरिक्त पुर्जे ही इस्तेमाल कीजिए।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कुत्ते की करामात

■ यह किस्सा कानपुर के एक ऐसे कटखने कुत्ते का है जिसने शहर भर की कानून और व्यवस्था को नंगाड़ा करके रख दिया. लोगों को इस कुत्ते के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए पुलिस को जो किलेबंदी करनी पड़ी वह किसी खतरनाक आतंकवादी से निबटने जैसी थी.

सभी कार्टून: अनिल शर्मा

पिछले पखवाड़े यहां के पुलिस अधीक्षक को किसी ने फोन पर खबर दी कि उसके घर में पांच-छह हथियारबंद बदमाश घुस आए हैं जिनमें से एक पुलिस की वर्दी में है. खबर मिलते ही अधीक्षक महोदय ने वायरलेस पर रेड एलर्ट का हुक्म दिया और कुछ मिनट बाद ही दर्जन भर अफसरों ने उस घर के इर्दगिर्द घेरा डाल दिया. किलेबंदी के बाद जब कुछ हथियारबंद पुलिस अफसर घर में दाखिल हुए तो अंदर स्थानीय चौकी के इंचार्ज को बैठे देख हैरान रह गए. वे मकान मालिक के कटखने कुत्ते के खिलाफ लिखाई गई रिपोर्ट के सिलसिले में आए थे और कुत्ते के डर के मारे मुहल्ले के कुछ लोगों को भी साथ लाए थे. पुलिस एक्शन की खबर सुनते ही आस-पास के मुहल्लों के लोग बाहर जमा हो गए और अपने-अपने जख्म दिखाते हुए वे कटखने कुत्ते तथा उसके मालिक की शिकायत करने लगे. अब भला इतनी बड़ी पुलिस फोर्स खाली हाथ कैसे लौटती. लिहाजा कुत्ते को बांधकर पुलिस हिरासत में ले लिया गया. मनमांगी मुराद पूरी होते देख कुछ उत्साही कुत्तापीड़ितों ने पुलिस वालों समेत मुहल्ले भर के लोगों को खूब मिठाई खिलाई.

पहले राम...

■ 'रामायण' की लोकप्रियता इन दिनों जिन बुलंदियों को छू रही है वह लोगों के लिए एक नया अनुभव है. लेकिन सीरियल की इस लोकप्रियता ने पिछले पखवाड़े महाराष्ट्र के सतारा जिले में ऐसा गुल खिलाया कि शादी के मंडप में बैठे समधी दिल के दौरे के शिकार होते-होते किसी तरह बचे.

लग्न का मुहूर्त सुबह 9.30 बजे का था. इसलिए हवन की अग्नि प्रज्वलित करने के बाद पंडित जी और वर-वधू पक्ष के लोग वधू के मंडप में आने का इंतजार कर रहे थे. पहले तो सब यही माने बैठे थे कि वधू के शृंगार में देरी लग रही है लेकिन मुहूर्त का समय निकलने पर भी वधू के दर्शन नहीं हुए तो लोगों की परेशानी बढ़ गई. वधू के कमरे में खबर लेने के लिए गए लोगों ने आकर खबर दी कि वधू गायब है और घर में कहीं भी उसका अता-पता नहीं है. इस खबर ने दोनों परिवारों में खलबली मचा दी. किसी ने यह कहकर हालात को और भी गंभीर बना दिया कि वधू को दूल्हा पसंद नहीं था इसलिए हो सकता है कि वह घर छोड़कर कहीं भाग गई हो. लिहाजा चारों ओर लोग दौड़ाए गए. उधर वर और वधू के माता-पिता की हालत ऐसी हो रही थी कि अब गश आया कि तब आया. अभी यह दौड़-धूप चल ही रही थी कि कुछ

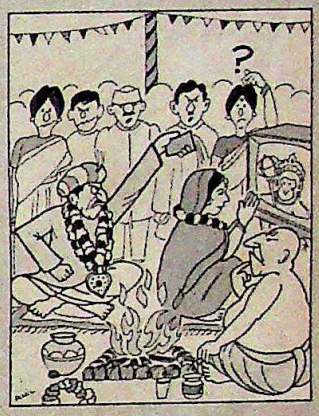

देर बाद शादी के जोड़े में सजी-संवरी और गहनों से लदी वधू अपनी सहेलियों के साथ घूंघट ओढ़े वहां हाजिर हो गई. पूछने पर पता चला कि वह 'रामायण' देखने के लिए पड़ोसी के घर चली गई थी.

अनोखी जोड़ी

■ पिछले दिनों मध्य प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने एक ऐसा पेचीदा मामला आ खड़ा हुआ जिसका हल न तो कानून की किताबों में है और न पुलिस नियमावली में. खबर आई कि विभाग की दो महिला कांस्टेबलों ने आपस में 'विवाह' कर लिया है. पुलिस की हथियारबंद शाखा में तैनात इन दोनों कांस्टेबलों का यह विवाह वैदिक रीति से हुआ. 'विवाह' को 'वर' और 'वधू' दोनों के परिवार वालों का आशीर्वाद प्राप्त था.

इस वैवाहिक संबंध की दूसरी खूबी यह रही कि विवाह के समय मंडप में 'वर' उर्मिला श्रीवास्तव शानदार टी-शर्ट और जींस में मौजूद थी और वधू लीला नामदेव परंपरागत दुलहन वाले वेश में थी. लीला के पति भी कांस्टेबल हुआ करते थे लेकिन दो साल पहले एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई. लिहाजा तीन बच्चों की जिम्मेदारी देखते हुए उसने पुलिस की नौकरी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया. उधर उर्मिला का विवाह तीन साल की उम्र में ही कर दिया गया था पर उसने युवा होने पर इस रिश्ते को अस्वीकार कर दिया और सामाजिक दबावों को देखते हुए पुलिस की नौकरी कर ली. नौकरी के दौरान उन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि दोनों ने इस दोस्ती को स्थायी रूप देने का फैसला कर लिया. फिलहाल पुलिस विभाग यह तय नहीं कर पा रहा है कि अपनी दो महिला कर्मचारियों की इस शादी को मान्यता प्रदान करे या नहीं.

मजाक है मजाक

■ मजाक को अगर गंभीरता से ले लिया जाए तो न सिर्फ उसका मजा किरकिरा हो जाता है बल्कि नई मुसीबत भी पैदा हो सकती है. बंबई के एक टेलीफोन एजेंट ने पिछले साल पहली अप्रैल के दिन एक ऐसा शगूफा छोड़ने का फैसला किया जो मजाक के नए पुराने सभी रिकार्ड तोड़ दे.

यह सोचकर एजेंट महोदय ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लैटर पैड लिये और उन पर दो पत्र लिख डाले. समाचारों के अनुसार दूरसंचार मंत्रालय के राज्य-मंत्री और महानगर टेलीफोन निगम के महाप्रबंधक के नाम लिखे गए इन पत्रों में निर्देश दिए गए थे कि अमुक-अमुक लोगों को टेलीफोन कनेक्शन जारी कर दिए जाएं. पर लगता है कि ये पत्र अपने गंतव्य पर अप्रैल-फूल दिन के बाद पहुंचे और तब तक ये संबंधित अफसर लोग भूल चुके थे कि मजाक क्या होता है. उन्होंने पत्रों को गंभीरता से लिया और मामला सीबीआइ तक जा पहुंचा जिसने जाली दस्तावेज तैयार करने के जुर्म में इन सज्जन को धर दबोचा. मगर किस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ. अब इन साहब ने विश्व रिकार्ड स्थापित करने वालों की पुस्तक 'गिनिज बुक' के संपादक को लिख भेजा है कि इतने बड़े 'अप्रैल-फूल' मजाक के लिए उनका नाम 'गिनिज बुक'

में प्रकाशित किया जाए. सिर्फ इतना ही नहीं, इन महोदय ने अब मांग की है कि उन्हें दूरसंचार मंत्री बना दिया जाए ताकि देश की दूरसंचार व्यवस्था सुधार जाए.

—संकलन: विजय क्रान्ति

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आज का शॉ वॉलेस

जहाँ दृष्टि बदले सृष्टि में

शॉ वॉलेस उद्यम के विविध आयाम।

गोंद, जिलेटिन, खमीर, शराब, चाय, जहाजरानी, खेती के साधन, औद्योगिक रसायन, जूते, डिटर्जेन्ट्स और शृंगार प्रसाधन...

शताधिक वर्षों में पनपी गतिविधियों का प्रकाशपुंज।

अब, छाबरिया समूह का एक अंश बनकर नई नई सीमाओं की ओर अग्रसर।

तेल निकासी और उपकरण, भूकंप सम्बन्धी सर्वेक्षण, टायर, स्थावर संपदा विकास, जैव तकनीक।

उद्यम की दुनिया में एक नये युग की ओर बढ़ते कदम।

शॉ वॉलेस यानि–
कल्पना. हिम्मत. कामयाबी

Shaw Wallace

छाबरिया समूह का सदस्य
वॉलेस हाउस, ४, बैंकशाल स्ट्रीट,
कलकत्ता ७०० ००१

TSA-SW-C-1-R

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पतन की पताका

वक्त के बहते दरिया में एक जुंबिश मात्र होता है एक पखवाड़ा, ऐतिहासिक दस्तावेज की शायद एक पंक्ति मात्र. लेकिन हर पखवाड़ा कोई-न-कोई विशिष्ट छाप छोड़ जाता है. बीते पखवाड़े ने अपनी जो छाप छोड़ी वह जैसे चेतावनी के लाल चिन्ह की तरह है. पतनोन्मुखता अब तक की उपलब्धियों को जैसे लीलती जा रही है.

और यह पतनोन्मुखता देश की राजनीति में, नेतृत्व के चरित्र में ज्यादा उजागर हुई है. एक तरह की हेकड़ी है जो बेवजह है लेकिन उतनी ही मुखर है जितनी नुकसानदेह भी. संसद की पवित्रता धूमिल कर दी गई है. राज्यसभा में अपनी ही पार्टी के सदस्यों और वरिष्ठ मंत्रियों तक से कहासुनी हो जाने पर सदन के सभापति इस्तीफा देने की पेशकश करते हैं. उनसे बहस में उलझने वाले यह भी भूल जाते हैं कि वे देश के उपराष्ट्रपति से मुखातिब हैं. और यह तो समझने की कोशिश भी नहीं की जाती कि उपराष्ट्रपति यह टकराव संसदीय प्रक्रिया की अस्मिता की रक्षा के लिए मोल ले रहे होते हैं. उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण यह है कि उनकी आलोचना नहीं होनी चाहिए भले ही संसदीय लोकतंत्र की बलि क्यों न चढ़ानी पड़े.

राज्यसभा के सभापति ने सदन में सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों से तीखी झड़प के बाद इस्तीफे की पेशकश की

देश के उपराष्ट्रपति को संसद में अगर यह घोषणा करनी पड़े कि 'अगर कांग्रेस पार्टी आज फैसला करती है कि मैं इस कुर्सी के लिए उपयुक्त नहीं हूं तो हाथ जोड़े हुए मैं यहां से निकल जाऊंगा. आप चाहें तो इस बारे में अपने नेता से बात कर सकते हैं' तो यह अपनेआप में एक बड़ी त्रासदी ही कही जाएगी.

मेघालय में संगमा ने लिंगडोह को फुसलाकर अपने खेमे में मिला लिया. वहां राजनैतिक आदर्शों को कूड़ेदान के हवाले कर दिया गया

और इन सबसे नेतृत्व की छवि एक बार फिर धूमिल ही हुई है. प्रधानमंत्री राजीव गांधी इस पूरे प्रसंग में चुपचाप तमाशाई जैसे बने रहे. उनकी चुप्पी कहीं ज्यादा मुखर रही. वे सदन से गए भी तो भौंडेपन से मुस्कराते हुए. पूर्व राष्ट्रपति संजीव रेड्डी ने अफसोस जाहिर किया, "पता नहीं राजीव कभी-कभी ऐसा क्यों कर बैठते हैं. आज नहीं तो कल यह उनके खिलाफ ही जाएगा." ऐसे में कुछ भी अनुल्लंघनीय नहीं बचा—न तो किसी संस्था और न ही किसी सम्मानित हस्ती की प्रतिष्ठा.

भगवंत सिंह नेगी

वकीलों की देशव्यापी हड़ताल के कारण पूरी न्यायिक व्यवस्था ठप होकर रह गई है

इसके लक्षण सब ओर दिखते हैं. किसी असावधान राज्य सरकार से बिना पूछे अचानक उस पर आधी रात नया राज्यपाल थोप दिया जाता है. शासकीय कायदे-कानून तय करने के लिए बने आयोग की सिफारिशें अनदेखी कर दी जाती हैं. मेघालय में मंत्रालय और निगम नीलामी पर चढ़ा दिए जाते हैं. राजनैतिक आदर्शों को कूड़ेदान के हवाले कर दिया जाता है. जनता के प्रतिनिधि पाला बदलने की उछल-कूद करते हैं. राजनीति अब बिकाऊ जिंस जैसी हो गई है जिसकी कीमत अदा करनी पड़ रही है जनता को.

प्रदीप तुकरपा

विपक्ष ने राजीव के इस्तीफे और मध्यावधि चुनाव की मांग के लिए दिल्ली में एक बेअसर-सी रैली आयोजित की

लेकिन यह सब कुछ अविश्वसनीय-सा भी लगता है. 80 करोड़ की आबादी इस त्रासद फरेब को मूक दर्शक की तरह देखती रहती है और फरेब दिन-ब-दिन गहरा ही होता जाता है. राजधानी में घटी एक घटना पर वकीलों की देशव्यापी हड़ताल हो जाती है. अलगाववादी आंदोलन को बेकाबू होने दिया जाता है और देश के एक उपजाऊ क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस-नहस होती है महज इसलिए कि वह विपक्ष शासित राज्य का क्षेत्र है.

और विपक्ष राजीव के इस्तीफे और मध्यावधि चुनाव की मांग पर राजधानी में कमजोर रैलियां करवा रहा है. एक बड़ी पार्टी भाजपा इस रैली का बायकॉट करती है तो इससे तो यही उजागर होता है कि चुनाव के लिए उनकी तैयारी कितनी लचर है.

यानी बीते पखवाड़े का संकेत क्या है? राजनैतिक हेकड़ी ने, जो दिन-ब-दिन ज्यादा से ज्यादा उग्र होती जा रही है, देश की संस्थाओं को ही नहीं व्यक्तियों की नसों में बहते खून को भी फीका कर दिया है. और यह एक खतरनाक बात है.

—दिलीप बॉब

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

केंद्रीय मंत्रिमंडल

बेकार

जरा भी संदेह हो तो मंत्रिमंडल में फेरबदल कर डालो—लगता है राजीव गांधी आजकल इसी सिद्धांत पर चल रहे हैं. इसीलिए वे लगातार अपने मंत्रिमंडल में उलटफेर करते रहे हैं. लेकिन इस कवायद का मतलब हमेशा अस्पष्ट ही रहा है. और मंत्रिमंडल के ताजा फेरबदल यानी 23 महीने के अंदर 23वें और बड़े पैमाने पर 12वें फेरबदल से तो जबरदस्त उलझन उजागर होती है.

मंत्रिमंडल में 59 सदस्य हो जाने के बावजूद न तो यह क्षेत्रीय दृष्टि से संतुलित लगता है, न इसमें नई प्रतिभाओं को मौका मिला है और न ही राजनैतिक रणनीति की कोई खास दिशा दिख पड़ती है. वैसे इतना भारी-भरकम मंत्रिमंडल पिछले 30 वर्षों में बहुत ही कम बार रहा है. लेकिन लगता है इस बार का फेरबदल बजट सत्र भर के लिए ही है. उसके बाद फिर बदलाव होगा.

देश के एक तिहाई राज्यों को मंत्रिमंडल में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है. फेयरफैक्स और प्रतिरक्षा सौदों के घोटालों पर संसद में राजीव का जोरदार पक्ष लेने वाले दिनेश सिंह को छोड़कर किसी भी अन्य संभावित व्यक्ति को मंत्रीपद नहीं दिया गया है. दिनेश सिंह जल संसाधन मंत्री बनाए गए. फेरबदल के बाद भी चार मंत्रियों को अतिरिक्त विभागों का जिम्मा दिया गया.

हरिकिशन लाल भगत को संसदीय कार्य के अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ऊर्जामंत्री वसंत साठे को वाणिज्य,

कार्टून: अजीत नाइनन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

की उलटफेर

मोतीलाल वोरा को नागरिक उड्डयन के साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और शहरी विकासमंत्री मोहसिना किदवई को पर्यटन विभाग का अतिरिक्त भार सौंपा गया है. इंका के एक वरिष्ठ सांसद कहते हैं, "जिन जगहों पर किसी की जरूरत नहीं थी वहां भी लोगों को रखा गया है. कुछ क्षेत्रों में तो अतिरिक्त जगह बनाकर नियुक्तियां की गई हैं, जैसे कि वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री का एक और पद बनाकर एडुआर्डो फेलिरो को रखा गया है." भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी के मुताबिक, "इस फेरबदल का न तो प्रशासनिक तर्क समझ में आता है, न राजनैतिक." प. बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु भी कहते हैं, "मंत्रिमंडल में फेरबदल केंद्र में इंका सरकार की अस्थिरता को जाहिर करता है."

लेकिन यह फेरबदल कई राजनैतिक मजबूरियों के कारण हुआ. बोफोर्स धमाका खत्म होने के बाद अब राजीव अपनी पार्टी और देश को यह जताना चाहते हैं कि वे ही अकेले बॉस हैं और राजनैतिक ढांचे पर उनकी पूरी पकड़ है. खुद उनके ममेरे भाई अरुण नेहरू समेत अनेक विपक्षी नेता कहते आ रहे थे कि राजीव में फेरबदल करने का दम नहीं रह गया है और अगर ऐसा हुआ तो पार्टी में विद्रोह हो जाएगा. लेकिन फेरबदल के बाद पार्टी के कोषाध्यक्ष सीताराम केसरी ने कहा, "हमारे नेता ने एक बार फिर चुनौती देने वालों को करारा जवाब दिया है. अब उन लोगों को कंधे पर लटककर जान दे देनी चाहिए. बगावत की कौन कहे, किसी ने चूं तक नहीं की. राजीव गांधी ही इंका और देश के निर्विवाद नेता हैं." मध्य प्रदेश इंका के पूर्व अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने कहा, "इस मंत्रिमंडल में न सिर्फ प्रतिभाशाली लोगों को ही मौका दिया गया है बल्कि आर्थिक और समाजिक रूप से पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों को भी इसमें जगह दी गई है."

फेरबदल का दूसरा कारण संसद का बजट अधिवेशन था. एक भरी-पूरी टीम लेकर और खाली स्थानों को भरकर वहां पहुंचने की जरूरत थी. फिर मंत्रीपद चाहने वालों का दबाव भी था. किसी तरह ऐसे लोगों को फिलहाल संतुष्ट रखने की जरूरत भी थी. मार्च के आखिर तक राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं और उस समय तक छह मंत्रियों समेत 60 सांसदों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा. तब राजीव को मंत्रिमंडल में इससे भी बड़ा फेरबदल करने की जरूरत पड़ेगी. उनके सलाहकारों का कहना है कि तब तक के लिए कामचलाऊ प्रबंध जरूरी था.

पार्टी सूत्रों के अनुसार फेरबदल असंतुष्ट सांसदों को दो हाथ दूर रखने के ख्याल से किया गया. पिछले चार हफ्तों से 100 से अधिक सांसद नई दिल्ली में डेरा डाले प्रधानमंत्री निवास से फोन का इंतजार कर रहे थे. बुलावा आया भी तो उनके लिए जो राजधानी में नहीं थे. इंका महासमिति के एक सदस्य ने कहा, "जिन लोगों को लिया गया है उनके बारे में कोई शिकायत नहीं कर सकता." जैसे कि एक सांसद कहते भी हैं, "जिन लोगों को मंत्री बनाया गया वे मुख्यमंत्री और प्रदेश इंका अध्यक्ष रह चुके हैं. उन लोगों को तो रखना ही था. इसी तरह अल्पसंख्यकों और पिछड़ी जातियों के मामले में भी शिकायत नहीं हो सकती. उनके लोग भी रखे ही जाने थे. फिर दिनेश सिंह के नाम पर भी कोई एतराज नहीं हो सकता क्योंकि हर आदमी का मानना था कि केंद्र में किसी अनुभवी ठाकुर की भी जरूरत है."

चार्ट: बी.के. शर्मा

क्षेत्रवार प्रतिनिधि

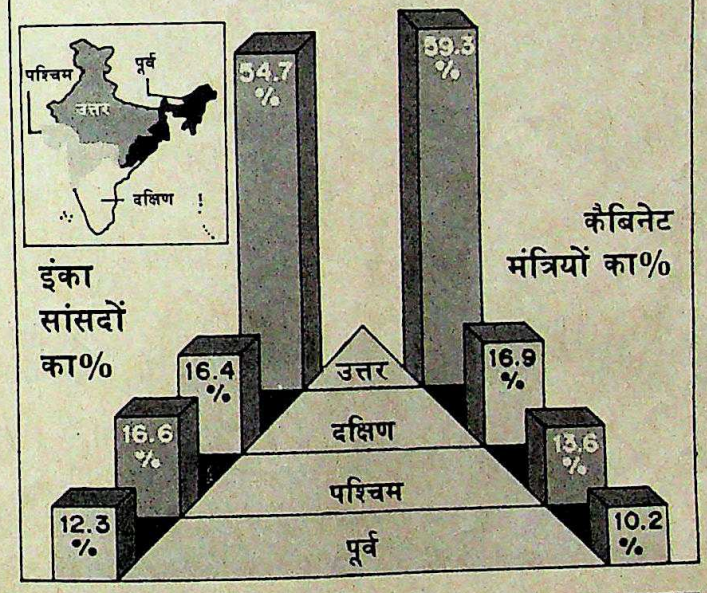

फेरबदल के बाद मंत्रिमंडल में आए 13 नए चेहरों में से 11 हिंदीभाषी प्रदेशों के हैं. दक्षिण को महत्वपूर्ण पद और संख्या दोनों के लिहाज से अपर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है

प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार क्षेत्रीय और सामाजिक भावनाओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए फेरबदल जरूरी था. हरिजनों की संख्या सात से बढ़कर नौ हो गई है. दिनेश सिंह को शामिल करने के बावजूद ठाकुरों की संख्या पांच से गिरकर तीन ही रह गई (देखें चार्ट). सबसे नाटकीय बढ़ोतरी ब्राह्मणों की संख्या में हुई है. 1985 में 10 ब्राह्मण मंत्री थे. यह संख्या अब 15 हो गई है. 16 सदस्यीय नए मंत्रिमंडल में भी आधे ब्राह्मण हैं. इनमें तिवारी, फोतेदार, वोरा, बिंदेश्वरी दुबे, साठे, नरसिंह राव, कृष्णचंद्र पंत और खुद प्रधानमंत्री (ब्राह्मण परिवार से जुड़ाव के कारण) शामिल हैं.

इससे इंका के वरिष्ठ लोग भी शिकायत करने लगे हैं कि ब्राह्मणवाद मंत्रिमंडल में ही नहीं, देश पर भी हावी हो रहा है. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और छह हाई-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कोर्टों के मुख्य न्यायाधीश, अगले सेना प्रमुख, प्रधानमंत्री और कैबिनेट सचिव, ब्राह्मण हैं.

ब्राह्मणों के अलावा मंत्रिमंडल में 21 ऊंची जाति के लोग, तीन ईसाई (एम.एम. जैकब, एडुआर्डो फेलिरो और मार्गरेट अल्वा) तथा एक सिख गृहमंत्री बूटा सिंह हैं. दो नए लोगों—जाफर शरीफ और रफीक आलम को शामिल करने के बावजूद मुसलमानों की संख्या छह से घटकर चार रह गई है. मुस्लिम समुदाय से अब अकेली मोहसिना किदवई ही कैबिनेट मंत्री रह गई हैं.

अगर इस फेरबदल में राजीव की कोई चुनावी रणनीति दिखती है तो यही कि वे हिंदी इलाके के हिंदुओं को अपनी ओर खींचना चाहते हैं. 13 नए चेहरों में से 11 बिहार और उत्तर प्रदेश के हैं. राज्यमंत्री से कैबिनेट मंत्री बनने वाले रामनिवास मिर्धा और वोरा तो अभी विधायक ही हैं.

कांग्रेसी नजरिये से इस फेरबदल का एक सुखद पहलू यह है कि महावीर प्रसाद, डूमरलाल बैठा, दुबे और वोरा सरीखे पुराने कांग्रेसियों को मंत्री बनाया गया है. इन लोगों के लिए पार्टी के अलावा कोई और काम नहीं है और आम आदमी भी उन तक आसानी से पहुंच सकता है. एक सांसद कहते भी हैं, "मंत्रियों तक पहुंचना दिन-ब-दिन मुश्किल होता जा रहा था और इसका इलाज भी शायद यही था. यह महत्वपूर्ण नहीं कि उन्हें क्या पद मिला है. वे अन्य मंत्रियों के साथ मिलकर इस बात के लिए दबाव डालेंगे कि पार्टी कार्यकर्ताओं के हक में भी फैसले हों, चाहे वे उन्हें रियायत के रूप में हों या ठेके दिलाने के रूप में."

पर पार्टी के ही कुछ अन्य लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री द्वारा चुने गए

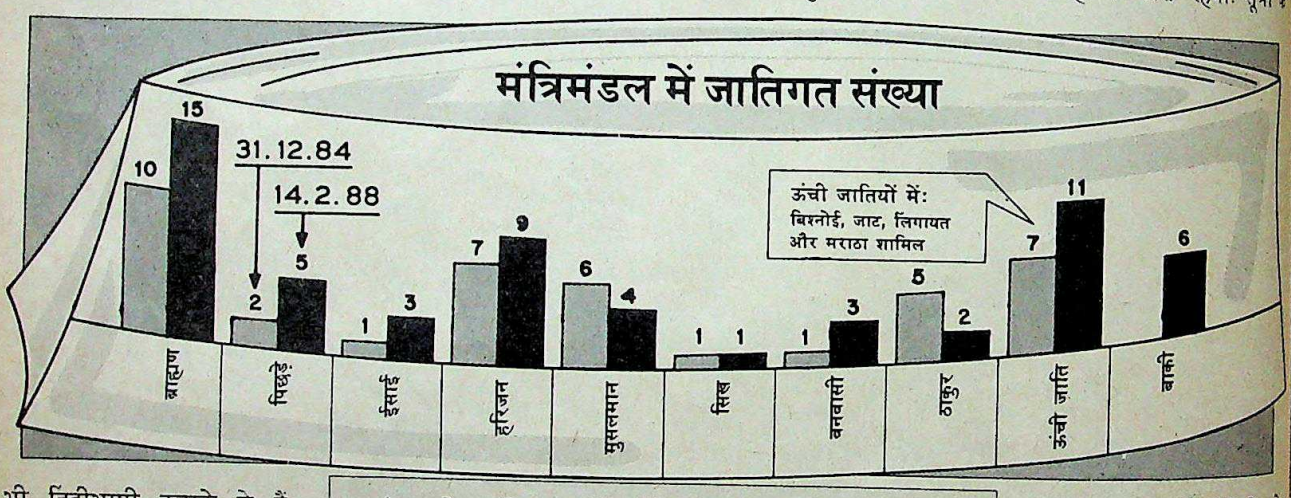

इंका के वरिष्ठ लोग शिकायत कर रहे हैं कि हाल के फेरबदल से ब्राह्मणों को फायदा पहुंचा है जबकि पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व दिए जाने के मामले में पक्षपात किया गया

भी हिंदीभाषी इलाके से हैं. दक्षिण को महत्वपूर्ण पद और संख्या दोनों के लिहाज से अपर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है (देखें चार्ट). दूसरे इलाकों से चुने गए दक्षिण भारतीयों नरसिंह राव और शिवशंकर समेत दक्षिण के मंत्रियों की गिनती 12 तक ही पहुंच पाई है. नरसिंह राव मंत्रिमंडल में दूसरे नंबर पर हैं. एक अन्य दक्षिण भारतीय जे. वेंगलराव उद्योगमंत्री जैसे प्रमुख पद पर हैं तो आर. प्रभु और पी. चिदंबरम उर्वरक और गृह मामलों के राज्यमंत्री हैं.

पूर्वी क्षेत्रों को अपेक्षतया सबसे कम प्रतिनिधित्व मिला है. इस क्षेत्र से इंका के हालांकि 69 सांसद हैं पर मंत्री सात लोगों को ही बनाया गया है. मजेदार बात यह है कि कैबिनेट स्तर के एक तिहाई मंत्री सीधे चुने हुए नहीं हैं. तिवारी, फोतेदार, शिवशंकर और भजनलाल राज्यसभा से हैं जबकि दुबे अधिकांश नए लोगों का न तो कोई व्यक्तित्व है, न आधार. वे दब्बू और स्वामीभक्त जरूर हैं. आलोचकों का मानना है कि इन लोगों का पिछला कामकाज भी कोई इतना अच्छा नहीं. उन्हें सिर्फ पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व देने के नाम पर रखा गया है. लेकिन इस मामले में भी जातिगत भेदभाव बरता गया है. वोरा और दुबे जैसे ऊंचे दर्जे के ब्राह्मण मुख्यमंत्रियों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया जबकि बैठा और महावीर प्रसाद जैसे प्रदेश इंका अध्यक्षों को उपमंत्री ही बनाया गया.

दिनेश सिंह की नियुक्ति पर भी कुछ विवाद हुआ. उनके समर्थक कहते हैं कि राजीव हर गांव में पानी पहुंचाने की बात जिस जोर-शोर से कहते हैं, उस हिसाब से जल संसाधन मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन दिनेश सिंह इस पद से खुश नहीं बताए जाते. ठाकुरों में नाराजगी है. ऐसे ही एक ठाकुर का कहना है, "राजीव गांधी कभी साधारण ठाकुर को क्यों नहीं चुनते? सिर्फ राजा दिनेश सिंह, कुंअर अर्जुन सिंह और महाराजा माधवराव सिंधिया जैसे सामंती ठाकुरों को ही उन्होंने चुना है."

केवल तीन महत्वपूर्ण विभागों के फेरबदल से किसी राजनैतिक योजना का संकेत मिलता है. जनार्दन पुजारी को बैंकिंग से ग्रामीण विकास मंत्रालय में भेज दिए जाने से लगता है कि उन्हें ग्रामीण वोटरों को लुभाने का जिम्मा सौंपा गया है. ग्रामीण विकास के लिए आवंटित 20,000 करोड़ रुपए के खर्च की व्यवस्था भी उन्हीं के पास रहेगी. सूत्रों के अनुसार एडुआर्डो फेलिरो को वित्त मंत्रालय में भेजने की वजह यह है कि सरकार प्रधानमंत्री के दोस्तों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन कानून के संभावित उल्लंघन संबंधी तीखे सवाल पूछे जाने की उम्मीद कर रही है. इसके पहले नारायणदत्त तिवारी अमिताभ बच्चन का बचाव करने में हिचकिचाते रहे हैं. फेलिरो से उम्मीद है कि जब कभी जरूरत हो वे साहसपूर्वक उनका बचाव कर सकें. तीसरे महत्वपूर्ण बदलाव यानी जगदीश टाइटलर को श्रम मंत्रालय में भेजे जाने से स्पष्ट है कि उनकी संगठनात्मक क्षमता को मजदूरों के हलके में वोट पक्के करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. फिलहाल यहां भाजपा और मार्क्सवादियों का दबदबा बढ़ता दिख रहा है. विपक्षी पार्टियां मजदूर संघों पर पकड़ मजबूत करने के लिए अगले 18 महीनों में सामूहिक विरोध की योजना भी बना रही

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

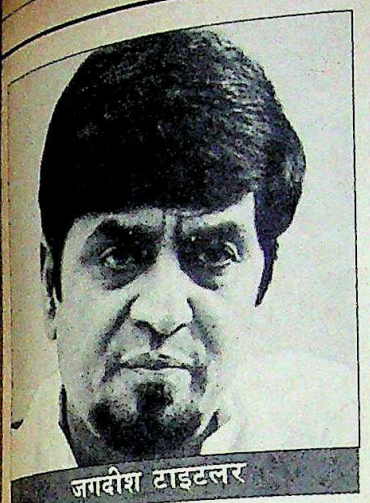
जगदीश टाइटलर

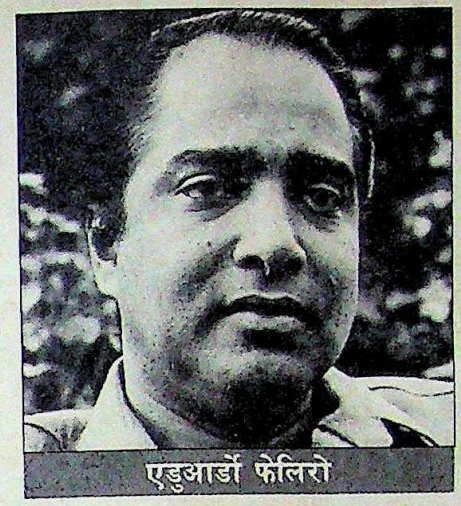
एडुआर्डो फेलिरो

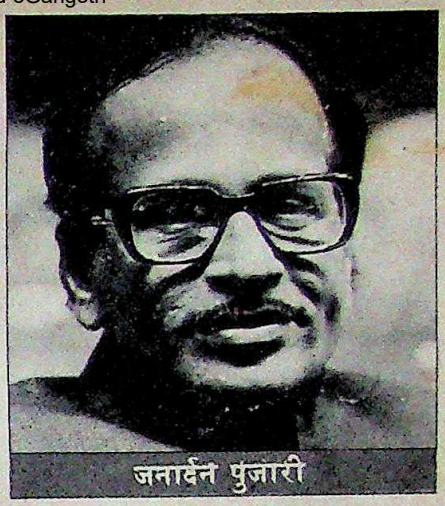
जनार्दन पुजारी

केवल तीन महत्वपूर्ण विभागों के फेरबदल से किसी राजनैतिक योजना का संकेत मिलता है. जगदीश टाइटलर को श्रम, एडुआर्डो फेलिरो को वित्त और जनार्दन पुजारी को ग्रामीण विकास मंत्रालयों में भेजा गया

है. कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष तारिक अनवर कहते हैं, "प्रधानमंत्री ने सही काम के लिए सही लोगों को चुना है. नए मंत्रिमंडल में अनुभवी और युवा लोगों के बीच उम्दा संतुलन रखा गया है."

लेकिन राजनैतिक मजबूरियों को छोड़ दें तो यह फेरबदल अपने आप में कोई मायने नहीं रखता. क्योंकि मई में संसद सत्र की समाप्ति के बाद भी भारी फेरबदल किया जाना है. चार साल में पर्यटन विभाग में सातवां, वाणिज्य में चौथा, कानून में पांचवां, नागरिक आपूर्ति में सांतवां और सूचना एवं प्रसारण विभाग में पांचवां मंत्री बदला गया है. जाहिर है कि बहुत से परिवर्तन अंतिम समय पर अचानक कर दिए गए.

उदाहरण के तौर पर वोरा को 1 फरवरी को बताया गया कि उन्हें हटाया जाएगा और वे अगले आदेश का इंतजार करें. लेकिन नए विधानसभा सत्र के एक हफ्ते बाद 12 फरवरी तक उन्हें कोई आदेश नहीं मिला. राजीव को उनका उत्तराधिकारी ढूंढ़ने में खासी मुश्किल पेश आ रही थी. उस रात बूटा सिंह ने वोरा को बुलाकर त्यागपत्र देने को कहा. अगले रोज रात 8 बजे दिल्ली में अर्जुन सिंह को आधे घंटे के भीतर पालम पहुंचने और सीताराम केसरी के साथ भोपाल जाने को कहा गया. उसी रात उन्हें पार्टी की बैठक में चुना जाना था.

बंगलूर में जाफर शरीफ को रात एक बजे सूचना दी गई कि वे तुरंत दिल्ली पहुंचें. वे दिल्ली की सुबह वाली उड़ान पकड़ने के लिए सात घंटे गाड़ी चलाकर मद्रास पहुंचे. फिर भी शपथ ग्रहण के लिए उन्हें देरी हो गई. उत्तर प्रदेश के आधे जिलाधिकारी तो महावीर प्रसाद को ढूंढ़ रहे थे. वास्तव में 13 नए मंत्रियों में से छह बाद में हुए समारोह में ही शपथ ग्रहण कर सके. यहां तक कि अपने नए मंत्रियों के चेहरे भी राजीव नहीं पहचानते थे. शपथ ग्रहण करने आई सुमति ओरांव की उपस्थिति में ही राजीव अपने एक सहयोगी से पूछते सुने गए कि वे महिला कौन हैं.

कुल मिलाकर यह एक दिखावटी फेरबदल है. इसमें बमुश्किल ही कोई राजनैतिक मजबूती दिखती है. दो मंत्री गुरदयाल सिंह ढिल्लों और रामदुलारी सिन्हा हटाए तो गए पर सिन्हा को केरल का राज्यपाल बना दिया गया

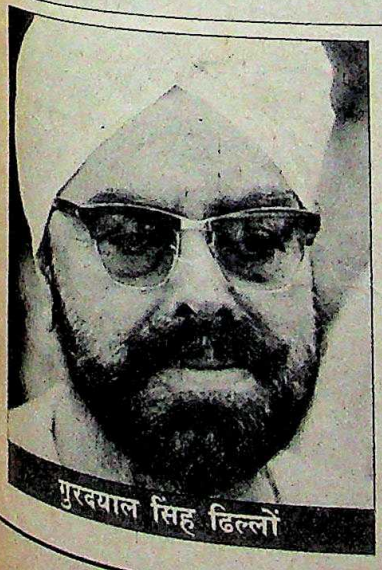
गुरदयाल सिंह ढिल्लों

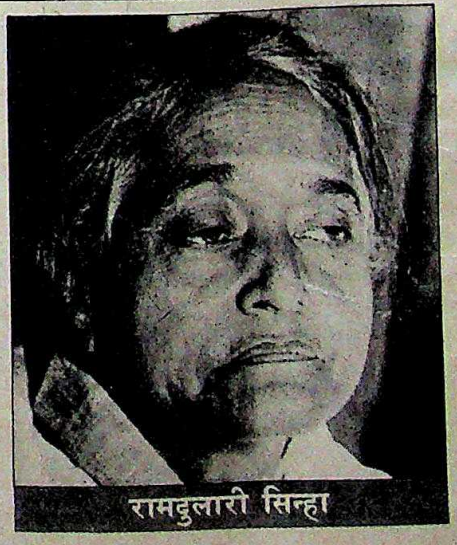
रामदुलारी सिन्हा

कुल मिलाकर यह एक दिखावटी फेरबदल था. इसमें बमुश्किल ही कोई राजनैतिक मजबूती दिखती है. दो हटाए गए मंत्रियों गुरदयाल सिंह ढिल्लों और रामदुलारी सिन्हा में से सिन्हा को केरल का राज्यपाल बना दिया गया. हिंदीभाषी इलाके के एक सांसद इस पूरे फेरबदल पर सटीक टिप्पणी करते हैं, "राजीव गांधी के सामने दो तरह के लोग थे. एक तो वे जिन्हें किसी पद की चाह थी और दूसरे वे जो कोई पद दिए जाने के योग्य थे. उन्होंने ऐसे लोगों को भरती किया जिन्हें पद की चाह थी, उन्हें नहीं जो उसके योग्य थे."

—प्रभु चावला और इंद्रजीत बधवार

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

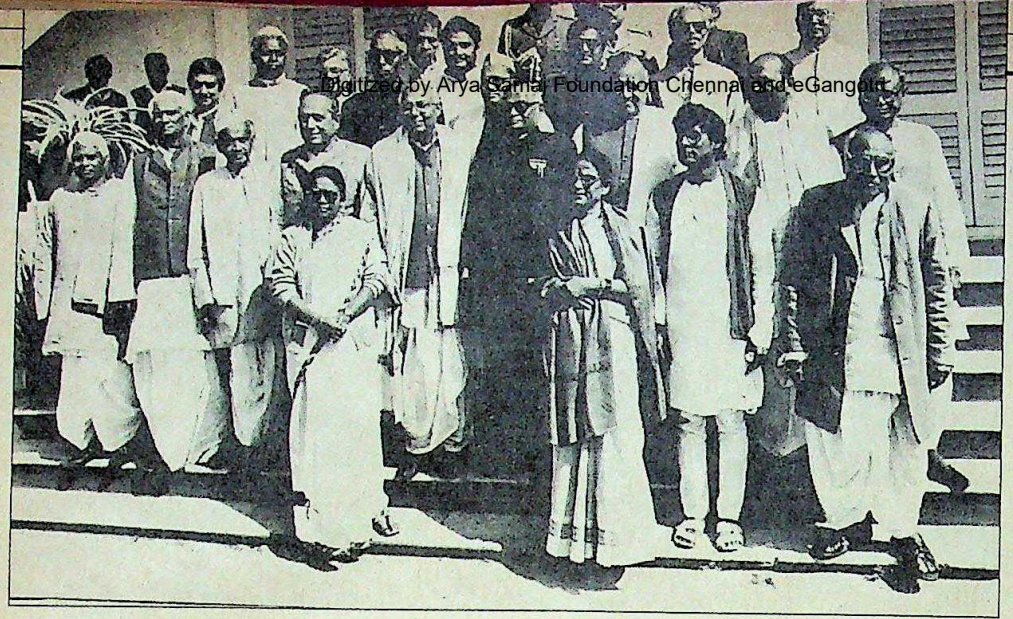

कृष्ण मुरारी किशन

बिहार

परिवर्तन की उम्मीदें

पर आजाद के चयन की प्रक्रिया से असंतोष भी उभरा

बिहार में जिस परिवर्तन की उम्मीद लंबे समय से की जा रही थी वह आखिरकार पिछले महीने हो ही गया. भागवत झा आजाद को नया मुख्यमंत्री बनाने से इस पिछड़े राज्य में जहां परिवर्तन की कुछ उम्मीदें बंधीं, वहीं उनके चयन के तरीके पर कुछ असंतोष भी पैदा हुआ. जिस बैठक में उन्हें 'आम राय' से चुना गया उसमें इंका विधायक दल के 240 में से 85 सदस्य ही मौजूद थे. एक नाराज इंका विधायक ने कहा, "यह एक लोकतांत्रिक तख्तापलट था."

बिंदेश्वरी दुबे की जगह आजाद को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने का पार्टी अध्यक्ष राजीव गांधी का फैसला 13 फरवरी की देर रात को ही मालूम हुआ. कुछ घंटों के भीतर आजाद विमान से पटना रवाना हो गए. सीमा सुरक्षा बल के विशेष डकोटा विमान में उनके साथ दुबे, 22 विधायक और चार पार्टी पर्यवेक्षक—वित्तमंत्री नारायणदत्त तिवारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री बी. शंकरानंद, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री दरबारा सिंह और इंका महासचिव नरेंद्र चतुर्वेदी (बिहार मामलों के प्रभारी) थे.

इस बीच पटना में अधिकांश पार्टी विधायकों से संपर्क करने में जुट गए और उन्हें इंका विधायक दल की बैठक के लिए आमंत्रित करने लगे. लेकिन 60 विधायकों से ही संपर्क हो पाया. बैठक की सूचना मिलने पर उन्हें ताज्जुब ही हुआ. लगभग 80 विधायक पटना से बाहर नई दिल्ली में अपने सामान्य काम, गुटबाजी में व्यस्त थे. उन्हें पटना आने के लिए कोई विमान न मिल सका.

ऐसी जल्दबाजी से हर कोई आश्चर्यचकित रह गया. वरिष्ठ पार्टी नेताओं का कहना था कि उसी सुबह चूंकि दुबे को केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिए शपथ दिलाई जाने वाली थी इसीलिए इतनी जल्दबाजी की जरूरत पड़ी. लेकिन इस पर बहुत कम लोगों को भरोसा हुआ. आम धारणा यह थी कि यदि पार्टी आकाओं ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए ज्यादा समय दिया होता तो पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार बन जाते. विधायक दल के नेता के चुनाव के समय मिश्र दिल्ली में थे. बाद में उन्होंने आजाद को अपने गुट की ओर से पूरा समर्थन

आजाद का मंत्रिमंडल: असंतुलित

देने की बा
जिस त
उस पर
मुख्यमंत्री दे
चुनौती दे
मुनने की
तो इससे
कहना थ
प्रशासन में
है और अ
(देखें बॉक्
नहीं है.
उग्रवादी
अलग वनन
है; नियमि
और धनब
गिरोह फि
हालांकि
पसंद बहुत
तरह अपन
उनका सा
में से (मं

भागवत झा आजाद

सख्ती के संकेत

"हे प्रभु मुझको शक्ति दो कि मैं अपने प्रदेश और अपनी जनता की यथाशक्ति भलाई और सुप्रगति के कार्य कर सकूं."

बिहार के नए मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद ने 15 फरवरी को राज्य सचिवालय के अपने कार्यालय में प्रवेश करने के तुरंत बाद उपरोक्त शब्द कागज के एक टुकड़े पर लिखे. बिहार में व्याप्त सड़ांध को दूर करने के लिए 60 वर्षीय आजाद को सचमुच ईश्वर के सहारे के साथ-साथ राज्य के राजनीतिकों और नौकरशाहों के सहारे की भी जरूरत होगी.

हृदय से कवि, शिक्षा से अर्थशास्त्री और विचारों से समाजवादी आजाद बिहार सरकार के जातिगत और भ्रष्टाचारी स्वरूप को बदल देने के लिए कमर कसे नजर आ रहे हैं. वरिष्ठ इंका नेताओं को लगता है कि आजाद को सख्ती से शासन चलाने का निर्देश दिया गया है. आजाद कहते हैं, "लोगों का व्यवस्था पर से विश्वास ही उठ गया है. मैं उनमें फिर से विश्वास जगाना चाहता हूं."

और वाकई, शुरू के कुछ दिनों के उनके व्यवहार ने नौकरशाही और राज्य इंका नेताओं में सनसनी फैला दी. बिलकुल साफ-सुथरे अंदाज में आजाद ने कई खुशामदी और मतलबी विधायकों और अधिकारियों को दरकिनार कर दिया. साफ है कि आजाद के आगे चापलूसों की नहीं चल पाएगी. दुबे सरकार के एक राज्यमंत्री ने जब उन्हें माला पहनाने की कोशिश की तो शिष्टाचारवश मुस्कराने के बजाय आजाद ने उनसे कहा, "मैं देख रहा हूं कि आप तीसरी बार माला लेकर आए हैं. आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं जबकि आपके मंत्री बनने की कोई भी संभावना नहीं है?"

मुख्यमंत्री की इन टिप्पणियों ने पार्टी नेताओं और अधिकारियों को भौंचक तो किया ही, उनके शुरुआती फैसलों ने भी लोगों को कम नहीं चौंकाया है:

- विधायकों को अपने चुनाव क्षेत्र में काम करना चाहिए.
- सभी मंत्री 72 से 84 घंटों के भीतर अपनी फाइलें निबटा दें, इसके बाद फाइलें अपनेआप मुख्यमंत्री के पास पहुंच जाएंगी.
- किसी अधिकारी का एक बार तबा-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इंने की बात कही.

जिस तरीके से मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ उस पर विपक्षी नेताओं ने भी आजाद के मुख्यमंत्री पद पर बैठने की वैधानिकता को चुनौती दे दी. लेकिन मुख्यमंत्री को यह सब सुनने की फुरसत कहां थी. उनके दिमाग में तो इससे भी गंभीर समस्याएं थीं. उनका कहना था, "मेरा मानना है कि राज्य प्रशासन में पूरी तरह से अराजकता फैली हुई है और अधिकारी कोई काम नहीं कर रहे." (देखें बॉक्स). यह कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है. मध्य बिहार के सात जिलों में उग्रवादी समानांतर सरकार चला रहे हैं; अलग वनवासी राज्य की मांग बढ़ती जा रही है; नियमित अंतराल से नरसंहार हो रहे हैं और धनबाद की कोयला खानों में माफिया गिरोह फिर से संगठित हो रहे हैं.

हालांकि मंत्रियों के चयन में आजाद की पसंद बहुत सीमित थी, फिर भी उन्होंने किसी तरह अपना 23 सदस्यीय मंत्रिमंडल बनाया. उनका साफ कहना था, "मुझे तो उन्हीं लोगों में से (मंत्री) चुनने थे." इसलिए ताज्जुब नहीं कि कुछ बदनाम लोग भी मंत्रिमंडल में जगह पा गए. आधा दर्जन मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं जबकि एक पर 'हत्या' तक का आरोप है.

बहरहाल आजाद ने मंत्रिमंडल की छवि बदलने की कोशिश जरूर की. उन्होंने दुबे सरकार के सात कैबिनेट मंत्रियों और 15 राज्यमंत्रियों को अपनी टीम में शामिल नहीं किया. मिश्र भी घाटे में नहीं रहे क्योंकि उनके पांच समर्थक आजाद मंत्रिमंडल में शामिल किए गए. इनमें उनके भतीजे अमरेंद्र मिश्र भी थे जिन्हें दुबे ने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया था. आजाद ने टीम का चयन करते समय विधानसभा अध्यक्ष शिवचंद्र झा, सेवादल प्रमुख तारिक अनवर और केंद्रीय राज्यमंत्री ललितेश्वर प्रसाद शाही के समर्थकों की भी अनदेखी की.

लेकिन जातिगत प्रतिनिधित्व के हिसाब से मंत्रिमंडल में बेहद खामियां हैं, ऐसा इंका नेताओं का मानना है. उनका कहना है कि चुनाव के समय यही खामियां भारी पड़ सकती हैं. मसलन भूमिहारों को तीन जगहें मिली हैं जबकि ठाकुरों को उनकी उम्मीद के उलट दो ही जगहें मिल पाई— वह भी ऐसे समय जब इंका को विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व वाली ठाकुर लॉबी का सामना है. केंद्र में भी उनका कोई प्रतिनिधि नहीं है. जहां तक पिछड़े वर्गों का सवाल है, लड़ाकू यादवों और कुर्मियों को कुल पांच मंत्रीपद मिले हैं लेकिन अपेक्षाकृत कम प्रभावशाली कोइरियों को अनदेखा कर दिया गया. नौकरशाही में हावी कायस्थों का भी मंत्रिमंडल में कोई प्रतिनिधि नहीं लिया गया. इतना ही नहीं, 22 जिलों की तो अनदेखी ही कर दी गई.

लेकिन आजाद का मानना है कि उनका मंत्रिमंडल 'ठोस और चुस्त' है. वे कहते हैं, "मैं समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दूंगा पर गुटबाजी को बढ़ावा नहीं दूंगा. मेरी दिलचस्पी तो कुछ कर दिखाने में है." और इसकी शुरुआत उन्होंने एक ही तरह का काम करने वाले कई विभागों को तीन बड़े विभागों में जोड़कर की है. ये हैं—जल संसाधन विकास, मानव संसाधन विकास और स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग.

मिश्र कहते हैं, "आजाद ने बदनाम लोगों को दूर रखने की कोशिश तो की पर फिर भी ऐसे कुछ लोग मंत्रिमंडल में घुस आए हैं. साफ-सुथरी सरकार मुहैया करने की लोगों की उम्मीदें जगाने के बाद उन्हें भविष्य में अधिक कठोरता से काम लेना होगा."

दरअसल जैसे ही वे अपनी स्थिति मजबूत करने की ओर रुख करेंगे इन्हीं उम्मीदों को पूरा करना उनके लिए भारी पड़ने लगेगा. —फरजंद अहमद

कृष्ण मुरारी किशन

दला होता है तो उसके पास दो ही विकल्प होंगे— तबादले का आदेश माने अथवा निलंबन भुगते.

• सार्वजनिक उद्यमों में खर्च का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया जाए. ठेकेदारों और इंजीनियरों को उनके अधीन चल रहे काम का जवाबदेह माना जाएगा.

उनके ये फैसले उनकी एक ऐसे व्यक्ति की छवि को ही पुष्ट करते हैं जो झुकने के बजाय टूट जाना पसंद करता है. इंका विधायकों को अभी भी वह वाकया याद है

दुबे के साथ आजादः समस्याओं का बोझ

जब 1980 में इंदिरा गांधी ने उन्हें उपमंत्री बनाने की पेशकश की थी तो वे राष्ट्रपति भवन से निकल आए थे. उनका तर्क था कि वे किसी के अधीन काम नहीं कर सकते. एक साल बाद उन्हें वही मंत्रालय स्वतंत्र रूप से सौंपा गया था.

कमजोर और ढुलमुल दुबे के जाने के बाद आजाद का चुना जाना आशान्वित तो करता है लेकिन यह भी साफ है कि उन्हें अपना रास्ता तय करने में संकटों का सामना करना पड़ेगा. एक बड़े अधिकारी ने कहा, "हमें चिंता इस बात की है कि आजाद की छवि कभी एक धैर्यवान नेता की नहीं रही." पार्टी के कुछ नेताओं का भी मानना है कि अपनी मनमानी शैली के कारण आजाद पार्टी के सभी धड़ों को साथ ले चलने में शायद कामयाब नहीं हो पाएंगे. आधा दर्जन बार सांसद चुने जा चुके राज्य के नए हाकिम को अपना पूरा समर्थन देने वाले जगन्नाथ मिश्र ने कहा, "वे साफ-सुथरे, ईमानदार और सक्षम प्रशासक हैं, लेकिन बिहार की जटिल हालत के लिए कुछ चतुराई भी जरूरी है." और साथ ही भाग्यशाली होना भी.

—फरजंद अहमद

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

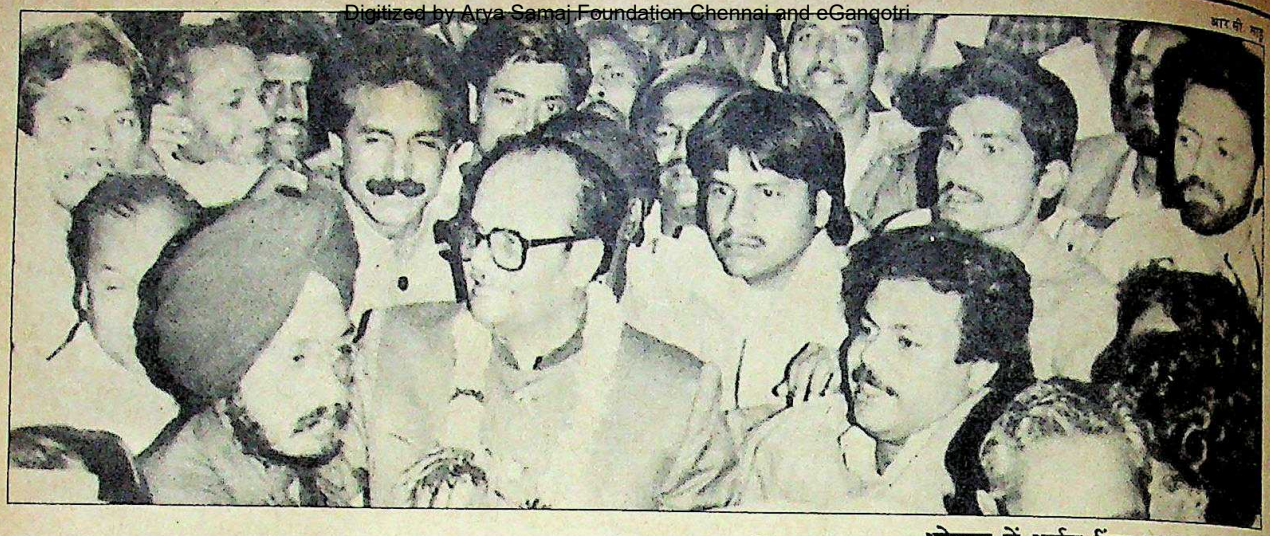

भोपाल में अर्जुन सिंह का स्वागत

मध्य प्रदेश

अर्जुन की घर वापसी

राजनैतिक गहमागहमी बढ़ने के साथ ही फेरबदल की उम्मीद

सब कुछ जैसे किसी माफिया गुट की पोशीदा करतूत की तरह हो रहा था. आधी रात को जल्दबाजी में बुलाई गई बैठकें, परदे के पीछे जबरदस्त लॉबिइंग, गुपचुप मुलाकातें और दनादन घनघनाती फोन की घंटियां. और इस सबके पटाक्षेप पर मध्य प्रदेश ने पाया कि उसके 59 वर्षीय मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा को नई दिल्ली में कैबिनेट मंत्री बनाने के लिए उठा ले जाया गया. उनकी जगह भोपाल में उनके पूर्ववर्ती और केंद्र में कैबिनेट मंत्री 57 वर्षीय अर्जुन सिंह को बैठा दिया गया. उधर राज्य के विधायकों को इस प्रक्रिया से अलग ही रखा गया—उनमें से ज्यादातर को तो इस तख्ता पलट की खबर सुबह अखबारों से ही मिली.

इस नाटक की शुरुआत 12 फरवरी को दोपहर में वोरा को टेलीफोन पर दिल्ली बुलाने से हुई. मुख्यमंत्री को विधानसभा से उठकर दो बार बाहर जाना पड़ा. उस दिन शाम को वे विमान से नई दिल्ली रवाना हो गए. रात में उन्होंने बूटा सिंह से भेंट की और आधी रात तक वे दुबारा भोपाल लौट आए. वहां इंतजार कर रहे पत्रकारों को उन्होंने बताया कि "उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन के मद्देनजर कानून और व्यवस्था की स्थिति पर विचार-विमर्श करने के लिए उन्हें दिल्ली बुलाया गया था." लेकिन ऐसे संकेत थे कि वोरा को एक महत्वपूर्ण टेलीफोन संदेश की प्रतीक्षा करने और केंद्र में पहुंचने को तैयार रहने के लिए कहा गया था.

आखिरकार जब 13 फरवरी को टेलीफोन आया तब वोरा राजभवन में एक भोज में थे. फोन के दूसरी तरफ बूटा सिंह उनसे इस्तीफा देने और फौरन दिल्ली पहुंचने को कह रहे थे. इसके तुरंत बाद वोरा ने अपने घर पर मंत्रिमंडल की एक अनौपचारिक बैठक में साथियों से कहा कि उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया है.

इसके बाद इंका विधायक दल के सचिव वीरेंद्र तिवारी से नए नेता के चुनाव के लिए दूसरे दिन शाम 5 बजे बैठक बुलाने को कहा गया. और 5 बजकर 5 मिनट पर वोरा अपनी गाड़ी पर लगे झंडे को ढककर अपना इस्तीफा राज्यपाल को देने राजभवन पहुंचे. लौटकर पत्रकारों से कहा, 'आलाकमान के आदेश का पालन' किया है.

वाकई उन्होंने ऐसा ही किया. पर उस वक्त मुरैना जिले के सबालगढ़ में गए केंद्रीय रेल राज्यमंत्री माधवराव सिंधिया से टेलीफोन पर बात करने के बाद ही. वोरा के राजनैतिक रहनुमाओं में एक—सिंधिया अपने कार्यक्रम रद्द कर तुरंत कार से ग्वालियर आए और वहां से उसी रात दिल्ली के लिए रेल में बैठ गए. बताया जाता है कि उनकी यह भाग-दौड़ अर्जुन सिंह को मात देने के लिए थी. लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी.

उधर भोपाल में एक और घटना घट गई. वोरा ने तिवारी को दुबारा बुलाकर उनसे विधायक दल की बैठक अगले दिन शाम के बदले उसी रात को बुलाने को कहा.

इसी बीच राजभवन से संपर्क कर आधी रात को शपथ ग्रहण की तैयारी करने को कहा गया. लेकिन उस समय तक राज्यपाल के.एम. चंडी सोने जा चुके थे. इसलिए शपथ ग्रहण का समारोह दूसरे दिन सुबह तक टालना पड़ा.

अर्जुन सिंह राज्य सरकार के एक विमान से आधी रात को ही भोपाल पहुंच गए थे. वोरा और उनके मंत्रियों के साथ सत्तारूढ़ पार्टी के कई नेताओं ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया. वहां से वे सीधे विधायक दल की बैठक में शामिल होने प्रदेश इंका के दफ्तर पहुंचे. उनके साथ आलाकमान के दो प्रतिनिधि—हरिकिशनलाल भगत और सीताराम केसरी थे. ये दोनों ही दिल्ली में उनके प्रबल विरोधी हैं. बैठक दस मिनट में ही समाप्त हो गई. इंका की जानी-पहचानी परंपरा के अनुसार मोतीलाल वोरा ने अर्जुन सिंह का नाम राज्य के 20वें मुख्यमंत्री के लिए प्रस्तावित किया.

बैठक की जल्दबाजी का राज यह था कि वोरा को केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ लेने सबेरे ही दिल्ली पहुंचना था. लेकिन जल्दबाजी में लोकतांत्रिक उसूलों को ताक पर रख दिया गया. विधानसभा चार दिन के लिए स्थगित होने के कारण ज्यादातर विधायक अपने क्षेत्रों में चले गए थे. 248 इंका विधायकों में से सिर्फ 35 ही बैठक में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शामिल हो पाए थे. यह संख्या 50 सदस्यों के कोरम से भी कम थी.

विपक्ष के नेता, भाजपा के कैलाश जोशी ने कहा, "लोकतांत्रिक प्रक्रिया से गुजरने के दिखावे तक को दरकिनार कर दिया गया." लेकिन नए मुख्यमंत्री ने इसे सिरे से ही नकार दिया. "मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री की इच्छा पूरी करने में किसी विधायक को हिचकिचाहट रही होगी."

अगले आम चुनावों पर नजर रखते हुए ही अर्जुन सिंह को वापस बुलाया गया है. वे विनम्र राजनीतिक हैं और राजनैतिक दांव-पेंचों में माहिर भी. पिछले चुनाव में उन्होंने झोंपड़पट्टीवासियों को जमीन के पट्टे देने, पिछड़े वर्गों के लिए नौकरी के अवसर और सुविधाएं बढ़ाने और छोटे किसानों के कोऑपरेटिव के कर्जे माफ करने जैसे फायदेमंद कदम उठाकर इंका को भारी जीत दिलाई थी. वोरा को राजनैतिक दांवपेंच में कमजोर और दुविधाग्रस्त माना जाता है.

अर्जुन सिंह के समर्थकों के बढ़ते दबाव के कारण ही वोरा का पतन इतनी जल्दी हुआ. हालांकि वे अर्जुन सिंह के आशीर्वाद से ही गद्दी पर बैठे थे पर बाद में दोनों के बीच फासला काफी बढ़ गया. एक तरफ वोरा की शिकायत थी कि उनके पूर्ववर्ती दूर बैठकर उनकी सरकार अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके प्रतिद्वंद्वी के चेले वोरा की बेरुखी की शिकायत कर रहे थे.

नए मुख्यमंत्री ने पहले ही दिखा दिया कि वे अपने विरोधियों को बख्शेंगे नहीं. विरोधियों को सबक सिखाने और समर्थकों को पुरस्कृत करने के लिए उन्होंने नए मंत्रिमंडल में वोरा सरकार के 22 में से 12 मंत्रियों को नहीं लिया. यहां तक कि सिंधिया के एक समर्थक को भी निकाल दिया गया. ज्यादातर नए मंत्रियों में वे ही हैं जिन्होंने राज्य में नेतृत्व परिवर्तन का अभियान चला रखा था.

अर्जुन सिंह के लौटने का एक परिणाम तो यही होगा कि वोरा सरकार के दौरान स्वच्छंद हो गई अफसरशाही पर अब थोड़ा अंकुश लग जाएगा. राज्य सचिवालय, पुलिस मुख्यालयों और जिलों में बड़े पैमाने पर फेरबदल की उम्मीद है. और ज्यादा राजनैतिक गहमागहमी की उम्मीद के चलते राज्य के नेता और क्षेत्रीय अखबारों के मालिक अब दूसरा ही राग अलापने लग गए हैं.

—नरेंद्र कुमार सिंह

अर्जुन सिंह

'मेरी राय महत्वपूर्ण नहीं'

पंजाब और दिल्ली की राजनीति में तीन वर्षों तक पर्याप्त चर्चित रह चुकने के बाद 57 वर्षीय अर्जुन सिंह पिछले पखवाड़े मध्य प्रदेश की राजनीति में वापस लौटे. सौम्य, मृदुभाषी अर्जुन सिंह अपनी विशिष्ट, सुसंस्कृत मगर साजिशी राजनीति के लिए प्रसिद्ध रहे हैं. अपनी ही पार्टी के अपने प्रतिद्वंद्वी के पछाड़े

भवान सिंह

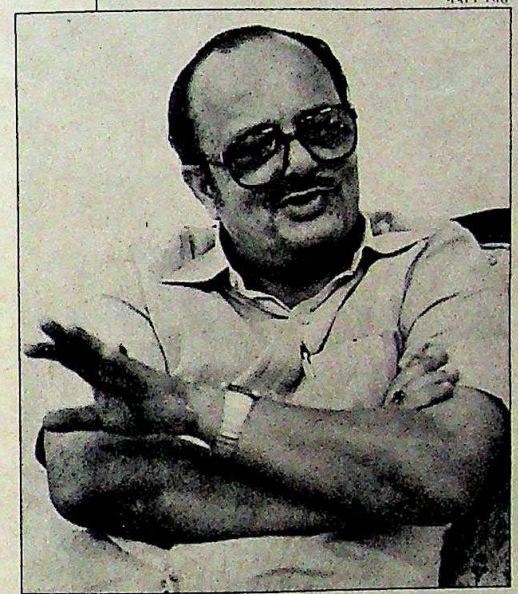

जाने के बाद आत्मविश्वास से भरे अर्जुन सिंह ने इंडिया टुडे के प्रमुख संवाददाता **नरेंद्र कुमार** *सिंह से बातचीत की. उसके अंश:*

● ***आपने हाल के राजनैतिक घटनाक्रम को मामूली फेरबदल बताया है. पर ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी?***

इस बारे में मेरी राय महत्वपूर्ण नहीं है. फैसला प्रधानमंत्री ने सारी बातों को ध्यान में रखकर किया है. पार्टी को अगले आम चुनाव तक कई चुनौतियों का सामना करना है. उन्होंने इन बातों और राज्य की स्थिति को ध्यान में रखकर फैसला किया होगा.

● ***पर आपके मंत्रिमंडल ने तो वोरा सरकार के कामकाज की तारीफ की?***

स्वाभाविक ही था यह क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं था जिसकी निंदा की जानी चाहिए थी. पिछली संरकार की असफलता के कारण यह सरकार नहीं बनी है. इसीलिए मैंने कहा कि यह मामूली फेरबदल है.

● ***कांग्रेस विधायक दल की बैठक का समय बदलने की क्या जरूरत थी जिससे यह सारा कुछ आधी रात में हुए नाटक जैसा लगा? भोपाल के बाहर के विधायकों को बैठक की खबर नहीं मिली.***

जितना मैं जानता हूं वह तो यही है कि वोरा जी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने की वजह से जल्दबाजी की गई. मैं मानता हूं कि कई विधायक बैठक में आ नहीं सके.

● ***लेकिन अखबारों का कहना है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराने की रस्म अदायगी भी नहीं हुई.***

कई बार दिखावा भी जरूरी होता है, पर असलियत क्या है यह भी महत्वपूर्ण होता है. पार्टी में एकता है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी विधायक प्रधानमंत्री की इच्छा के प्रतिकूल काम करेगा.

● ***आपने जिस तरह मंत्रियों को चुना उससे लगता है कि आलाकमान ने आपको पूरी आजादी दे रखी थी.***

इंका के किसी मुख्यमंत्री के लिए यह मान लेना उसका दुस्साहस ही होगा कि वह सर्वेसर्वा हो गया है. मैंने प्रधानमंत्री को सरकार और संगठन के कामकाज पर बहुत बारीकी से ध्यान देते हुए देखा है. इससे मुख्यमंत्रियों का दायित्व बहुत बढ़ जाता है. मैंने इसमें यह ध्यान नहीं रखा कि वे किसके समर्थक हैं.

● ***निकाले गए कई मंत्रियों का मानना है कि यह भविष्य के घटनाक्रम का संकेत है कि आगे कड़ाई होगी.***

विस्तार के अगले चरण में किसे शामिल करना है या नहीं करना है इसका कोई पैमाना नहीं तय किया गया है. मैं अभी यह कह नहीं सकता कि आगे कौन लोग आएंगे और कौन नहीं. मैंने विधायकों की बैठक में भी साफ-साफ कह दिया है कि किसी के कामकाज और प्रतिभा पर कोई बाड़ नहीं लगी है.

● ***क्या अब आपने 'ना' कहना सीख लिया है? क्या हम आपके कामकाज के तरीके में कुछ बदलाव की उम्मीद करें?***

मुझे लगता है मैंने कुछ बातें सीखी हैं. मुझे बदलना भी चाहिए.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तमिलनाडु

मतदाताओं पर नजर

चुनावी शतरंज की बिसात पर दांवपेच शुरू

राज्य के राजनैतिक मंच के सभी कलाकार पिछले पखवाड़े तीन करोड़ मतदाताओं का दिल जीतने की रणनीति बनाने में व्यस्त रहे. अन्नाद्रमुक के एक गुट की नेता 38 वर्षीया पूर्व अभिनेत्री जयललिता मतदाताओं का दिल जीतने के मुहिम में बाकियों से एक कदम आगे दिखीं.

जयललिता की रणनीति जितनी विस्तृत है उतनी ही थका देने वाली भी. सुबह वे मद्रास के पोएस गार्डन के अपने आलीशान बंगले की बालकनी से छोटी-मोटी भीड़ को संबोधित करतीं, फिर झोंपड़पट्टियों में रह रहे लोगों से मिलने निकल पड़तीं. जनसभाएं संबोधित करने और पार्टी के बड़े नेताओं से चुनावी रणनीति पर बतियाने के लिए वे मदुरै और तंजावुर भी पहुंच चुकी हैं. दोनों जगह सभाओं में लाखों लोग पहुंचे. एक पूर्व मंत्री एस. तिरुनवुक्करसु ने कहा, "उन्हें अन्नाद्रमुक के नेता के रूप में स्वीकार कर लिया गया है. दिवंगत मुख्यमंत्री एमजीआर के बाद पार्टी को इतने कम समय में एकजुट करने में कोई समर्थ नहीं हुआ." अन्नाद्रमुक के दूसरे गुट द्वारा मदुरै और सालेम में आयोजित एमजीआर की विधवा जानकी की सभाओं में भारी भीड़ जुटी. (देखें बॉक्स).

लेकिन जयललिता का प्रदर्शन ज्यादा दमदार रहा है. लगता है हर तबके के राजनैतिक नेता भी इसे महसूस करने लगे हैं, तभी तो वे उनके गुट में मिलने की इच्छा से उनके घर पहुंचने लगे हैं. जानकी गुट के छह पूर्व विधायक और चार सांसद अपने समर्थकों के साथ उनसे मिलने गए. इसी तरह करुणानिधि के द्रमुक के एक सांसद भी.

जब जयललिता गुट ने मद्रास में सदस्यता अभियान शुरू किया तो एक ही दिन में 20,000 लोगों ने सदस्यता पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए. दिवंगत मुख्यमंत्री एमजीआर की खासमखास तथा मृदुभाषी पूर्व मंत्री पनरूती रामचंद्रन कहती हैं, "हमारी नेता जयललिता ने अन्नाद्रमुक पार्टी और मतदाताओं पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कई कदम उठाने की योजना बनाई है."

एमजीआर की लोकप्रियता के एक मुद्दे का इस्तेमाल करते हुए जयललिता पिछले पखवाड़े मद्रास की व्यासरपाडी झोंपड़पट्टी में गईं और वहां आग के कारण बरबाद हुए 15 परिवारों को मकान बनवाने के लिए 500-500 रुपए बांटे. दूसरी तरफ वे फिल्म उद्योग के अपने समर्थकों को एमजीआर के साथ वाली अपनी पुरानी फिल्में प्रदर्शित करने के लिए तैयार कर रही हैं. परदे पर एमजीआर की नायिका के रूप में दिखाया जाना उनके लिए चुनाव में निश्चित रूप से फायदेमंद ही साबित होगा.

उन्होंने दूसरे प्रमुख मुद्दे भी नहीं भुलाए. धान का कटोरा कहे जाने वाले तंजावुर के किसानों को जब पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा, तब जयललिता ने उनके हक में आवाज उठाई और कर्नाटक से अतिरिक्त पानी की मांग की. इस मामले में

जयललिता-जानकी

देवियों का द्वंद्व

पिछले पखवाड़े तमिलनाडु की जनता को आंसुओं, ग्लैमर और हद दर्जे की नाटकीयता का नायाब नमूना देखने को मिला. वजह यह थी कि जयललिता जयराम और एमजीआर की विधवा जानकी दिवंगत मुख्यमंत्री के राजनैतिक उत्तराधिकार पर अपना-अपना दावा लेकर मैदान में उतर आई थीं. सिद्धांतों और आदर्शों की ओट में इन दोनों महिलाओं की लड़ाई दरअसल व्यक्तिगत लड़ाई ही थी.

सबसे पहले मैदान में उतरीं जयललिता. उन्होंने एमजीआर की याद में तंजावुर और मदुरै में शोक सभाएं कर डालीं. जानकी पहले तो धैर्यपूर्वक सब देखती रहीं. पर पखवाड़े के आखिर में उन्होंने भी मदुरै और सालेम में सभाएं कीं और उनकी 24 दिन पुरानी सरकार गिराने के लिए इंका की तीखी आलोचना की. जानकी की सभाओं में जयललिता की सभाओं से कहीं बड़ी तादाद में महिलाएं मौजूद थीं. जानकी गुट को यकीन है कि तमिलनाडु की रूढ़िवादी जनता एमजीआर की रजतपट की प्रेमिका के बजाय उनकी विधवा को सहजता से स्वीकार करेगी.

उधर जयललिता ने अपनी सभाओं में एमजीआर की अंत्येष्टि के मौके पर अभिनेता दीपन द्वारा उनके साथ की गई

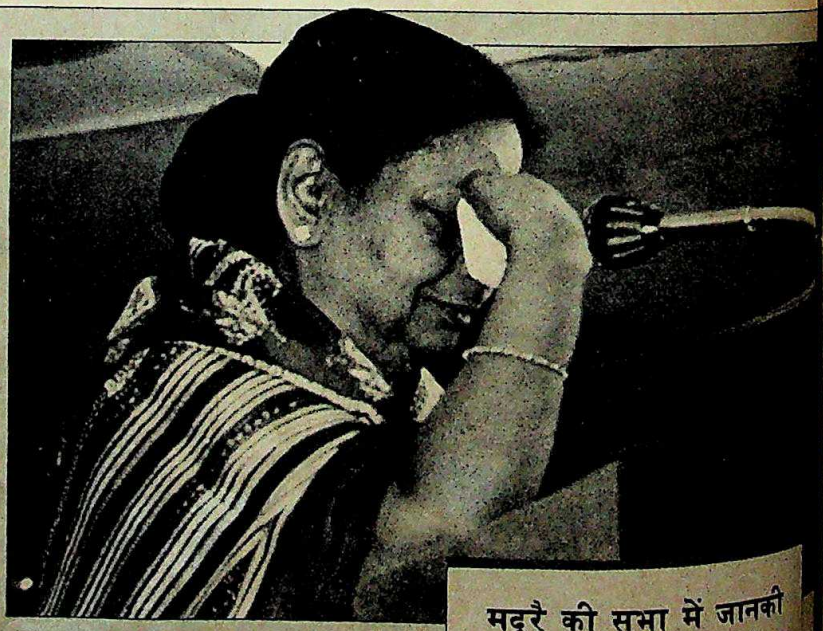

मदुरै की सभा में जानकी ने रो कर जनता की सहानुभूति जीत ली. यहां तक कि कई महिलाएं भी उनके साथ रो पड़ीं

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Foundation Chennai and eGangotri

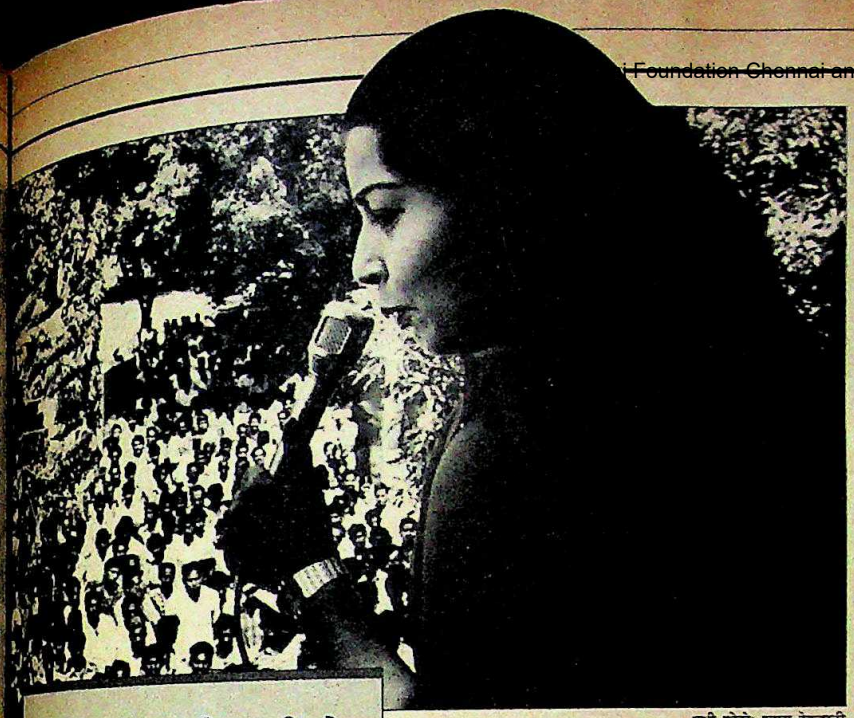

सभी फोटो: श्याम टेकवानी

मतदाताओं का दिल जीतने की मुहिम में इस खूबसूरत पूर्व अभिनेत्री ने राज्य के बाकी राजनीतिकों को बहुत पीछे छोड़ दिया है

बदसूरती को खूब उछाला. जयलिता ने नाटकीय स्वर में जनता से पूछा, "यदि पुरातची थलाइवार' (क्रांतिकारी नेता-एमजीआर) होते तो क्या कोई मेरी तरफ उंगली भी उठा सकता था?" सभा में आए लाखों लोग बोल उठे "नहीं, हरगिज नहीं." जयललिता ने अपनी प्रतिद्वंद्वी जानकी की भी जम कर आलोचना की.

जानकी ने मदुरै में अपने भाषण के अंत में आंसू बहाकर लोगों की सहानुभूति बटोरी. सुबकते हुए वे बोलीं, "मैं रोती हूं तो लोग मेरी आलोचना करते हैं. क्या मुझे रोने का भी हक नहीं? यदि आपके साथ ऐसा हो जाए तो क्या आप नहीं रोएंगे." सभा में आई महिलाओं पर इसका इतना असर हुआ कि कई तो जानकी के साथ ही रो पड़ीं. जानकी ने उनकी शैक्षणिक योग्यता पर उठाए जा रहे सवालों का भी जवाब दिया. वे बोलीं, "लोग कहते हैं कि सरकारी जिम्मेदारियां उठाने लायक शैक्षणिक योग्यता मुझमें नहीं है. मैं 40 वर्ष तक उस विश्वविद्यालय में पढ़ी हूं जिसे दुनिया एमजीआर के नाम से जानती है."

जानकी के भाषण का सारांश था कि उनके साथ धोखा किया गया है. वे एक गरीब विधवा हैं और उनकी राजनैतिक नासमझी का फायदा उठाकर राजीव गांधी ने उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से नीचे खींच लिया. उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास दिलाया गया था कि मतदान के समय या तो इंका तटस्थ रहेगी या पक्ष में वोट डालेगी. जयललिता पर उन्होंने सीधे कोई आक्षेप नहीं किया लेकिन यह काम उनके समर्थकों ने कर दिया.

इसके विपरीत जयललिता ने ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे उठाकर राजनैतिक परिपक्वता दिखाई. उन्होंने वायदा किया कि यदि चुनाव जीत गईं तो वे पांच वर्षों के भीतर कावेरी का पानी तंजावुर ले आएंगी. मदुरै में उन्होंने जीतने पर पूरी नशाबंदी लागू करने का वायदा किया.

लेकिन ये बातें सतही ही हैं. असल लड़ाई तो मतदाताओं का दिल जीतने की है, दिमाग जीतने की नहीं. द्रमुक और इंका ने अब तक सुनियोजित प्रचार शुरू नहीं किया है और दोनों महिलाओं के लिए मैदान खाली पड़ा है. सत्ता के दांवपेच में जब बाकी दल भी उतर आएंगे तो मुकाबला निश्चय ही संघर्षपूर्ण हो उठेगा.

—एस.एच. वेंकटरमनी

केंद्र से हस्तक्षेप करने और दोनों राज्यों के बीच कावेरी जल बंटवारे के पुराने मामले को निबटाने की उन्होंने मांग की. उनकी एक मांग यह भी है कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य के लिए बनी ऐसी तमाम योजनाओं को मंजूरी दी जाए जो दिल्ली में लटकी पड़ी हैं. राज्य की राजनीति और समस्याओं पर प्रधानमंत्री राजीव गांधी तथा बूटा सिंह से बातचीत करने के लिए उन्होंने राजधानी का ताबड़तोड़ दौरा भी कर डाला. इसके एक हफ्ते बाद वे कर्नाटक के मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े से अंतरराज्यीय विवादों के निबटारे के लिए बातचीत करने पहुंच गईं. जयललिता से मुलाकात के बाद हेगड़े ने कहा, "राजनीति के साथ ही और कई मसलों पर भी हमारी बातचीत हुई."

लेकिन जयललिता का सबसे पहला लक्ष्य तो पंचायत स्तर तक के पार्टी कार्यकर्ताओं पर अपनी पकड़ मजबूत करना ही है. 1980 में चुने गए पार्टी के 1,96,000 पदाधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनका समर्थन हासिल करने की योजना बनाई जा रही है. इस बीच वे 650 सदस्यों वाली महापरिषद में अपना बहुमत साबित करने में कामयाब रही हैं. पिछले महीने जब उन्होंने परिषद की दूसरी बार बैठक बुलाई तब पार्टी महासचिव के पद पर उनके चुनाव पर मुहर लगाने 500 से भी ज्यादा सदस्य पहुंचे. इसके पहले 20 जिलों के महासचिवों में से 14 ने उनके पक्ष में समर्थन जाहिर किया था. जयललिता के निर्देश पर अब शहर, जिला और पंचायत समितियों की बैठकें हो रही हैं और उनके समर्थन में प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं. पार्टी के सचिवों से कहा गया है कि वे अपनी-अपनी इकाइयों के जरिये जयललिता के समर्थन में स्थानीय अदालतों में हलफनामा पेश करें. इन प्रस्तावों को बाद में चुनाव आयोग के पास यह साबित करने के लिए पेश किया जाएगा कि उन्हीं का गुट असली अन्नाद्रमुक है. जयललिता गुट के एक उप-महासचिव डॉ. एच.वी. हांडे ने कहा, "एमजीआर के रहते हम पार्टी संगठन पर बहुत कम ध्यान दिया करते थे क्योंकि लोग उन्हीं से लगाव महसूस करते थे. अब हम उनकी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना चाहते हैं."

जयललिता गुट के पदाधिकारियों की फेहरिस्त देखने से लगता है कि युवकों के अलावा हरिजनों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं को साथ लाने पर जोर दिया गया है. लगता है कि जयललिता के ब्राह्मण होने के बावजूद पार्टी में उनकी लोकप्रियता पर कोई असर नहीं पड़ा है वरना पार्टी के हर 10 में से 9 कार्यकर्ता तमिलनाडु से ब्राह्मणों का वर्चस्व समाप्त करने की कसमें खाए बैठे हैं. यकीनन राज्य की राजनीति में व्यक्तित्व की ताकत ही सबसे ऊपर है. एक पूर्व मंत्री ने स्वीकार किया, "हमारा दल सैद्धांतिक रूप से प्रतिबद्ध न होकर नेता के प्रति प्रतिबद्ध है. पहले लोग सिर्फ एमजीआर को वोट दिया करते थे, अब जयललिता के पीछे चल रहे हैं."

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लेकिन अगर जयललिता अपनी पकड़ मजबूत बना रही हैं तो इंका और द्रमुक भी पीछे नहीं हैं. लगता है किसी सोची-समझी योजना के तहत ही इंका के वरिष्ठ महा-सचिव जी.के. मूपनार को तमिलनाडु का पार्टी अध्यक्ष बनाया गया है. उम्मीद है मूपनार राष्ट्रपति शासन के तहत राज्य प्रशासन का फायदा उठाकर अपनी पार्टी के लिए उचित वातावरण बनाने की कोशिश करेंगे.

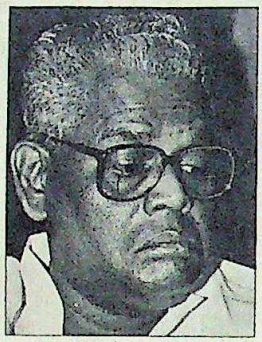

उधर राज्य सरकार ने तेजी से कामकाज शुरू कर दिया है. राष्ट्रपति शासन के एक हफ्ते बाद ही राज्यपाल पी.सी. अलेक्जेंडर के एक सलाहकार डॉ. एस.एस. सिद्धू को तमिलनाडु के विकास के लिए एक कम अवधि की योजना की रूपरेखा तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया. इस योजना पर नई दिल्ली में मूपनार, बूटा सिंह और राज्यमंत्री पी. चिदंबरम के बीच हुई बैठक में भी विचार हुआ था.

सिद्धू वही अफसर हैं जिन्होंने 1976 में गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के रूप में करुणानिधि की सरकार की बरखास्तगी में अहम रोल अदा किया था. अब उन्हें जनसंपर्क, आबकारी, बड़े उद्योग, खुफिया और आइएएस तथा आइपीएस अधिकारियों की नियुक्ति जैसे अहम मामले सौंपे गए हैं. इंका की योजनाओं के मद्देनजर उनकी नियुक्ति महत्वपूर्ण मानी जा रही है. अलेक्जेंडर और राजीव तक सिद्धू की सीधी पहुंच है.

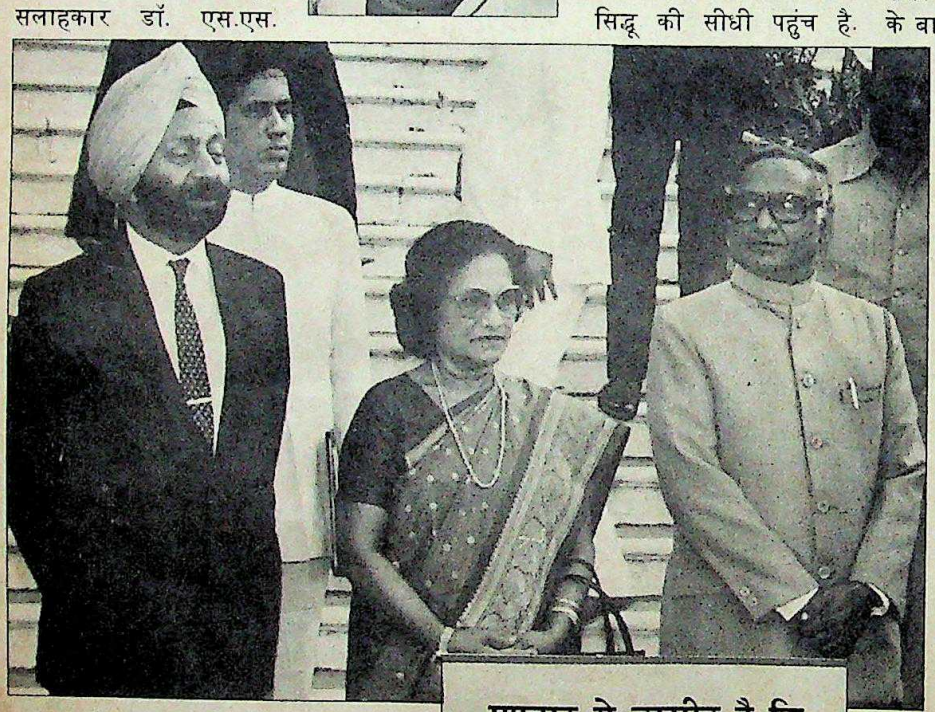

(ऊपर) मूपनार; और पी.सी. अलेक्जेंडर की पत्नी के साथ सिद्धू

मूपनार से उम्मीद है कि वे राष्ट्रपति शासन का लाभ उठा कर अपनी पार्टी के लिए जनता के बीच अनुकूल माहौल बनाएंगे

सिद्धू ने तमिलनाडु के विकास के लिए एक कम अवधि की योजना की रूपरेखा तैयार की है. इस योजना में हरिजनों के लिए अग्निरोधक घरों का निर्माण, अपंग बच्चों को वित्तीय सहायता, पानी की कमी वाले 125 इलाकों में पानी देने की व्यवस्था और किसानों को ट्रैक्टर और दूसरी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने जैसे लोकप्रिय नुस्खे भी शामिल हैं. इन योजनाओं के कारण अगले छह महीने में 200 करोड़ से भी अधिक रुपए खर्च होंगे लेकिन प्रधानमंत्री ने सैद्धांतिक तौर पर इसकी मंजूरी दे दी है. सिद्धू कहते हैं, "हमारी कोशिश राष्ट्रपति शासन के दौरान साफ-सुथरा और असरदार प्रशासन देना है. हम जिला स्तर पर जन शिकायत अधिकारी नियुक्त करने जा रहे हैं ताकि समस्याओं पर तुरंत गौर किया जा सके. हम प्रशासन को और फलदायी बना देंगे."

इसी बीच इंका अपनी विभाजित राज्य इकाई को संगठित करने की कोशिश कर रही है. पार्टी ने केरल के पूर्व मुख्यमंत्री के. करुणाकरन के साथ इंका महासचिवों, ऑस्कर फर्नांडिस और केदार नाथ सिंह को पार्टी की दुरुस्ती के लिए राज्य में भेजा है. ऑस्कर फर्नांडिस ने मदुरै और मद्रास के सभी प्रमुख पार्टी अधिकारियों से कहा है कि वे अपने मतभेद भुलाकर एक हो जाएं. तमिलनाडु युवा इंका के अध्यक्ष जयमोहन ने कहा, "अब हम चुनाव में किसी भी विरोधी का सामना करने की स्थिति में आ गए हैं."

लेकिन फिल्मी अभिनेता शिवाजी गणेशन और प्रदेश इंका के पूर्व अध्यक्ष सुब्रमण्यम के पार्टी से निकल जाने से समस्या खड़ी हो गई है. 30 सालों के साथ के बाद पार्टी छोड़ने वाले शिवाजी गणेशन ने 'तमिडग मुनेत्र कडगम' (तमिलनाडु प्रगतिशील मोर्चा) नाम की पार्टी बना ली है और वे पार्टी के पांच पूर्व विधायकों समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को अपने साथ तोड़ ले गए हैं. गणेशन ने कहा, "इंका नेतृत्व अब तमिलों के समर्थन को तय मान कर नहीं चल सकता. अगले चुनाव में मैं इंका को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करूंगा."

द्रमुक अध्यक्ष करुणानिधि ने कहा कि उन्होंने अभी 'प्रतिस्पर्धात्मक प्रचार अभियान' शुरू नहीं किया है. वे जयललिता पर 'काले धन का आसरा' लेने का इलजाम लगाते हैं. फिलहाल लगता है कि वे क्षेत्रीय पार्टियों पर इंकाई आधिपत्य के खिलाफ तमिल जनता की भावना भड़कने का इंतजार कर रहे हैं. इसी बीच वे पार्टी कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने में लगे हुए हैं.

राज्य में करुणानिधि को 25 फीसदी मतदाताओं का ठोस समर्थन पहले से ही हासिल है, अब उनकी कोशिश है कि इसमें 7 फीसदी की बढ़ोतरी हो जाए. ऐसा हुआ तो वे फिर सत्ता में आ सकते हैं. फिलहाल उनकी योजना श्रीलंका में भारतीय सेना की मौजूदगी पर बढ़ रही नाराजगी भुनाने की है. कुल मिलाकर लोगों को फिल्म पटकथा लेखक करुणानिधि या दो पूर्व अभिनेत्रियों—जयललिता और जानकी—में से किसी को चुनना है. इंका तो इस खेल में जोकर की तरह दिखती है.

—प्रभु चावला और मद्रास में एस.एच. वेंकटरमनी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

किरण बेदी

वकील नाराज

मामला जल्दी नहीं निबटेगा

राजधानी की पुलिस (उत्तरी जिला) उपायुक्त किरण बेदी का जल्द ही भारत की पहली महिला पुलिस उप-महानिरीक्षक बनने का पूरा संयोग बन गया था लेकिन पिछले पखवाड़े देश भर के लाखों वकीलों ने उनकी तरक्की के रास्ते में लगता है टांगड़ी अड़ा दी है.

दिल्ली की निचली अदालतों में जनवरी के मध्य में शुरू हुए आंदोलन (देखें इंडिया टुडे, 15 फरवरी) ने उस समय गति पकड़ी जब 17 फरवरी को बेदी के समर्थन में नारे लगा रही भीड़ तीस हजारी अदालत में बेदी विरोधी वकीलों पर टूट पड़ी. इस भीड़ ने पत्थर फेंके और दर्जनों वकीलों की कारों के शीशे तोड़ दिए. प्रदर्शनकारी वकीलों को पीटकर और उनके तंबू उखाड़कर रफूचक्कर हो गए.

इस घटना की तीखी प्रतिक्रिया हुई और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी मैदान में उतर आए. बहुत से वकील इसके लिए बेदी को ही जिम्मेदार ठहराते हैं. वरिष्ठ वकील गोविंद मुखौटी के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने बेदी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर 18 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी. 22 फरवरी को पूरे देश के करीब पांच लाख वकील भी इसमें शामिल हो गए. उस दिन उन्होंने पुलिस जुल्म के खिलाफ एक दिन की सांकेतिक हड़ताल रखी.

इससे सरकार हड़बड़ा गई. उसी दोपहर के बाद महान्यायवादी के. पारासरन ने हाईकोर्ट के दो न्यायाधीशों से जांच कराने के आदेश जारी किए. उपराज्यपाल हरिकिशनलाल कपूर ने दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से दो न्यायाधीशों के नाम मांगे जिन्हें जांच समिति में रखा जा सके. दोनों न्यायाधीश हफ्ते भर के भीतर तय करेंगे कि उनकी 90 दिन की जांच पूरी होने तक क्या किसी अफसर को मुअत्तल किया जाना चाहिए. जांच समिति 15 जनवरी को वकील राजेश अग्निहोत्री को हथकड़ी पहनाए जाने, 21 जनवरी को वकीलों पर हुए लाठीचार्ज और 17 फरवरी को तीस हजारी अदालत में हड़ताली वकीलों पर हुए हमले और तोड़-फोड़ की वारदातों की छानबीन करेगी.

दिल्ली के वकीलों की भूख हड़ताल; और (नीचे) बेदी

पर वकील वर्ग बेदी की तुरंत मुअत्तली से कम पर मानने को तैयार नहीं. बेदी दोषी हैं इस बारे में वकीलों को कतई शुबहा नहीं है. वरिष्ठ अधिवक्ता हों या और कोई, जिस किसी ने भी वकीलों की राय के खिलाफ दलीलें दीं या मामले का फैसला न्यायाधीशों पर छोड़ने की बात कही उसे वकीलों की सभा में 'विश्वासघाती' कहकर बैठा दिया गया. 22 फरवरी की इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट के सैकड़ों वकीलों ने जब तक बेदी को बरखास्त नहीं किया जाता तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखने का फैसला किया.

पर वहां मौजूद वरिष्ठ वकीलों के एक गुट ने बैठक का बहिष्कार किया. एक अलग बैठक में उन्होंने घोषणा की कि गोविंद मुखौटी की अध्यक्षता में हुई बैठक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की अधिकृत आमसभा नहीं है. इसमें तमाम बाहरी तत्व मौजूद हैं. इसके चलते सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के बहुमत का पक्ष अप्रभावी नजर आ रहा है. उन्होंने हड़ताल के मुद्दे पर अगले दिन गोपनीय मतदान कराने की मांग की पूर्व केंद्रीय कानूनमंत्री ए.के. सेन, वी.एम. तारकुंडे, सोली सोराबजी सरीखे कई वरिष्ठ वकील भी इस बैठक में मौजूद थे.

स्पष्ट है कि बेदी अपने आपको उतनी आसानी से निर्दोष साबित नहीं कर पाएंगी. वे अपने बचाव में दलील देती हैं कि "हिंसा शुरू होने तक भीड़ की मुझे जरा भी जानकारी नहीं थी." हालांकि भीड़ उनके अधीनस्थ इलाके के बीचोंबीच से दर्जनों टेंपों में भरकर दिन-दहाड़े तीस हजारी पहुंची थी. भीड़ जुटाने वाले इंका पार्षद राजेश यादव को हालांकि उन्होंने गिरफ्तार कर लिया लेकिन भीड़ जुटाने के लिए पुलिस वालों द्वारा रकम उगाहने और बांटने की खबरों पर बेदी कोई सफाई नहीं दे पातीं. वे उनका जोरदार खंडन भर कर दे रही हैं. उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कुछ वरिष्ठ वकीलों से भी मुलाकात की.

हालांकि उनकी इस दलील में दम दिखाई देता है कि आंदोलन चलने के दरम्यान उनके द्वारा हिंसा करवाना सरासर मूर्खतापूर्ण ही होता. उन्हें ही इसका नुकसान हुआ होता और हुआ भी है. मुखौटी भी कहते हैं कि "मुझे नहीं लगता कि दूसरी घटना के पीछे उनका हाथ रहा होगा. हां, लेकिन पहली घटना (वकीलों पर लाठीचार्ज) की जवाबदेही तो उन्हीं की है."

अगर वह भीड़ बेदी ने नहीं जुटाई थी तो फिर किसने जुटाई थी? इतना तय है कि खासकर नेताओं में उनके शत्रुओं की कमी नहीं है. उन्होंने कभी राजनीति के स्थानीय जागीरदारों को घास नहीं डाली. और यादव दिल्ली के राजनैतिक दिग्गज और केंद्रीय संसदीयमंत्री हरिकिशनलाल भगत के सहयोगी हैं. हालांकि भगत इस घटना में हाथ होने से स्पष्ट रूप से इनकार करते हैं. लेकिन राजनैतिक समीक्षकों का मानना है कि समझौते की कोशिश में लगे केंद्रीय गृहमंत्री बूटा सिंह को मुश्किल में देखकर वे कतई दुखी भी नहीं होंगे. अदालती जांच के नतीजे आने तक ऐसी अटकलें चलती ही रहेंगी.

—डेविड देवदास

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

राजस्थान

विपक्षी तलवारों पर सान

मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर के खिलाफ मुहिम में तेजी

शिवचरण माथुर के सत्ता में आते ही विपक्ष अपनी तलवारों पर सान चढ़ाने में जुट गया है. 21 फरवरी को जाट-बहुल भरतपुर जिले की डीग तहसील में हुई विपक्षी रैली इन्हीं बदलते समीकरणों का सार्वजनिक प्रदर्शन भर थी.

कहने को यह रैली डीग के पूर्व विधायक राजा मानसिंह की तीसरी पुण्यतिथि पर आयोजित की गई थी, पर राजनीतिक प्रेक्षकों को इसके पीछे दो मकसद साफ नजर आ रहे थे. एक, विपक्ष को सक्रिय करना क्योंकि दो सालों के बाद इसे फिर से वोटर से रूबरू होना है. दो, मानसिंह हत्याकांड को पूरे जोर-शोर से उठाकर मुख्यमंत्री माथुर को और इस बहाने कांग्रेस को परेशानी में डालना.

इस मुहिम को सिर्फ भरतपुर जिले की सीमा से निकालकर आगे ले जाने की गरज से रैली में कई राष्ट्रीय नेताओं को न्यौता दिया गया था. राजा मानसिंह की बेटी और निर्दलीय विधायक श्रीमती कृष्णेंद्र कौर उर्फ दीपा इस रैली की मुख्य कर्ताधर्ता बनीं. भरतपुर जिले के सभी विपक्षी दलों के लोग उनके साथ हुए. और उनके साथ था विपक्ष के नेता भैरोंसिंह शेखावत का आशीर्वाद. वैसे दीपा इससे पहले 27 जनवरी को मुख्यमंत्री निवास के बाहर एक दिन की भूख हड़ताल भी कर चुकी थीं. लेकिन विपक्ष ने मुहिम छेड़ने के लिए 21 फरवरी का दिन ही चुना.

लेकिन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर के शब्दों में कहें तो यह रैली नाकाम रही, "यह क्या रैली हुई जिसमें सात हजार लोग भी नहीं आए, वह भी अकेले भरतपुर जिले के." आयोजकों में से एक, विधायक यदुनाथ सिंह का कहना था कि सरकार के षड्यंत्र को देखते हुए यह संख्या भी बहुत है. रैली में लोग न आ सकें, इसके लिए सरकार ने 20 फरवरी की रात से ही सरकारी बस सेवा रोक ली थी.

इस आंदोलन का दूसरा चरण कितना कामयाब होता है यह तो होली के बाद ही पता चलेगा, फिलहाल इतना जरूर नजर आ रहा है कि जिस आंदोलन को विपक्ष की सक्रियता और एकता बढ़ाने के लिए जीवित किया गया था, उसने अंदरूनी दरारों को और गहरा कर दिया है. रैली में जनता पार्टी की अनुपस्थिति और लोकदल (ब) के अध्यक्ष नाथूराम मिर्धा की चुप्पी इसका प्रत्यक्ष सबूत है. रैली में जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री देवीलाल, जनमोर्चा के नेता अरुण नेहरू और भैरोंसिंह शेखावत ने राजा मानसिंह की हत्या के लिए शिवचरण माथुर को दोषी ठहराया और मुख्यमंत्री के रूप में उनकी पुनर्स्थापना को 'लोकतंत्र की हत्या' करार दिया, वहीं बेहद दमदार जाट नेता नाथूराम मिर्धा मौन रहे. उनकी नाराजगी की वजह यह बताते हैं कि शेखावत ने आंदोलन की मुख्य कमान लोकदल (अ) के विधायक यदुनाथ सिंह के पास क्यों जाने दी. यदुनाथ सिंह भरतपुर जिले में ही नदबई से विधायक हैं और यह रैली बुलाने वालों में दीपा के बाद नंबर दो कर्ताधर्ता हैं. मिर्धा को यह भी शुबहा था कि शेखावत लोकदल (अ) के जरिये यह आंदोलन उठवाकर जाट समुदाय में भी नेता बनकर छाना चाहते हैं.

मिर्धा अगर जाट वोट बैंक पर प्रभुत्व बनाए रखने के लिए इसे फैलाने के खिलाफ हैं तो जनता पार्टी का विरोध इस मुद्दे से ही है. बताते हैं कि विपक्ष के नेता शेखावत ने जब जनता पार्टी के नेता मानिक चंद सुराणा को कहा कि वे दीपा की भूख हड़ताल में शामिल हों तो सुराणा ने साफ इनकार कर दिया. उनका सवाल था, "मैं जनता को क्या जवाब दूंगा जब वह पूछेगी कि यह मुद्दा इतना ही गंभीर था तो पिछले तीन सालों के दौरान कोई इस पर एक शब्द भी क्यों नहीं बोला." लेकिन शेखावत का कहना है, "पिछले तीन साल के दौरान इसे उठाने की जरूरत ही नहीं थी. माथुर मुख्यमंत्री नहीं थे." शेखावत का कहना है कि यह आंदोलन इस बात के लिए है कि सरकार इस प्रकरण की पूरी जांच करवाने के लिए न्यायिक आयोग बिठाए. राज्य सरकार ने इस मांग को माना था और इसके लिए

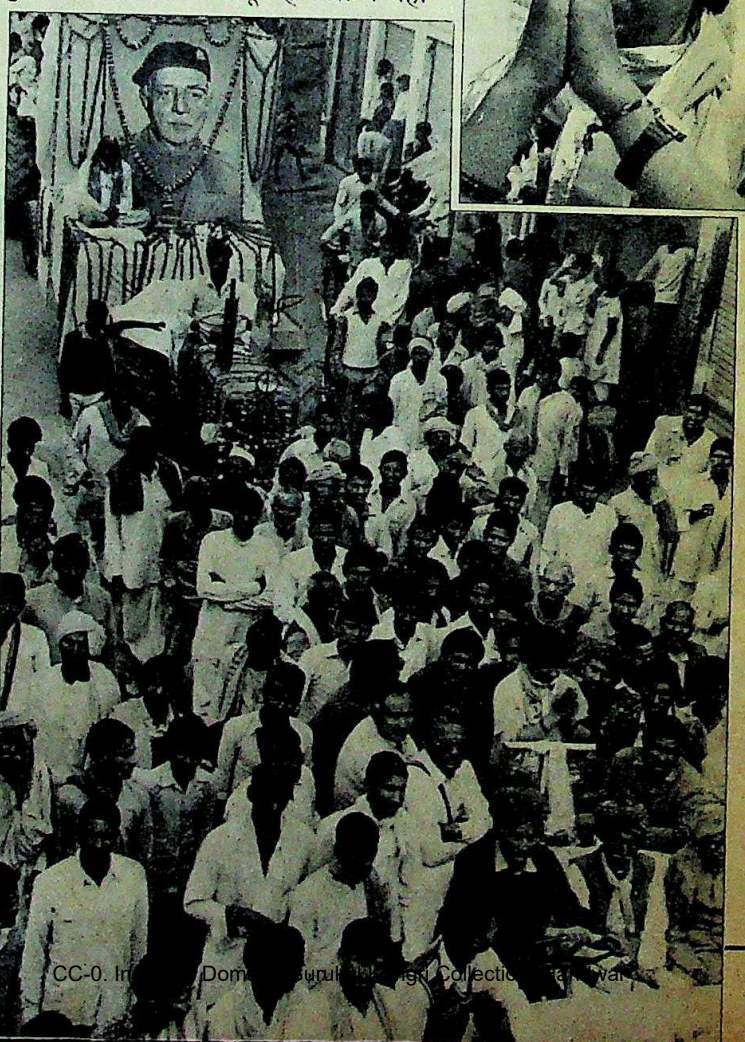

राजा मानसिंह की तीसरी पुण्यतिथि पर डीग में विपक्षी रैली का नेतृत्व किया उनकी बेटी दीपा (इनसेट) ने

CC-0. In... Dom... Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

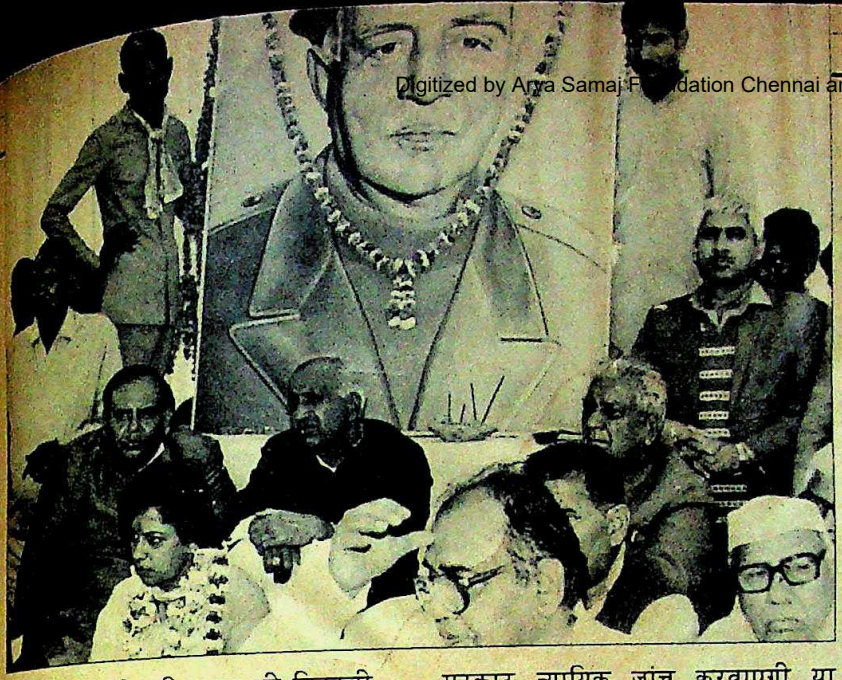

रैली में आए विपक्ष के दिग्गज ताकि इसे राष्ट्रीय स्वरूप मिले.

27 फरवरी '85 को अधिसूचना भी निकाली थी लेकिन बाद में जांच का काम सीबीआई को देकर यह अधिसूचना वापस ले ली गई.

उनका कहना है कि प्रधानमंत्री गांधी कोई अदालत नहीं हैं जो उनके कहने से हम मान लें कि माथुर इस कांड में निर्दोष हैं. इस संदर्भ में डीग में दिया अरुण नेहरू का बयान काबिलेगौर है. "मैं जानता हूं माथुर दोषी हैं. जिस समय प्रधानमंत्री ने उन्हें हटाने का फैसला किया था, मैं उनके पास ही बैठा था."

सरकार न्यायिक जांच करवाएगी या नहीं, इस सवाल को माथुर टाल गए. उनका कहना था, "विपक्ष को इसका जवाब विधानसभा में मिल जाएगा. लेकिन कोई कहे कि राजा मानसिंह की हत्या के लिए मैं जिम्मेवार हूं, एकदम बेबुनियाद बात है. मेरे उनसे हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं. अब एक घटना हो गई है तो उसके लिए किसे दोष दिया जाए."

इधर यह सवाल पिंगपोंग की गेंद की तरह इस से उस पाले में उछल रहा है तो उधर राजनैतिक हलकों में इस सवाल पर भी जोरदार अटकलबाजी जारी है कि इस आंदोलन के पीछे असंतुष्ट कांग्रेसियों की क्या भूमिका है. माथुर के मुख्यमंत्री बनने पर विदेश राज्यमंत्री और भरतपुर से सांसद नटवर सिंह की नाराजगी अब किसी से छिपी नहीं है. सिंह को आशंका है कि माथुर के मुख्यमंत्री बनने से और कहीं नहीं तो कम-से-कम भरतपुर में जरूर कांग्रेस की मिट्टी पलीद होगी. इन्हीं आशंकाओं का इजहार करते हुए नटवर सिंह के बेहद करीब समझे जाने वाले भरतपुर जिला देहात युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मधुवन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. अटकलबाजी इस बात को लेकर भी है कि इस आंदोलन के पीछे कहीं पिछले मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी तो नहीं हैं. इसकी वजह यह है कि माथुर उन्हें शेखावत और मिर्धा के काफी करीब मानते हैं.

इन तमाम समीकरणों के बावजूद कहना न होगा कि यह आंदोलन राजस्थान की राजनीति में जितने दिन जिंदा रहेगा, उतने दिन माथुर की नींद हराम रहेगी.

मानसिंह हत्याकांड

अदालती कार्रवाई

जयपुर के निर्माणाधीन बहुमंजिले मिनी सचिवालय की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक कमरा है जहां एक खाती की आरी से निकल रही चर्र-चूं काफी दूर से सुनी जा सकती है. चार मेजों और चंद कुर्सियों की जगह छोड़कर यह खाती एक प्लेटफार्म और दो कटघरे बना रहा है. जब ये बनकर तैयार होंगे तो उस अतिरिक्त सत्र न्यायालय (शहर) का हिस्सा बन जाएंगे जहां इन दिनों राजा मानसिंह हत्याकांड की सुनवाई हो रही है.

राजा मानसिंह: विवाद जारी

जुलाई 1985 में सीबीआइ ने मामले की तहकीकात करके जिस अदालत में चालान पेश किया था, वह अदालत यह नहीं थी. पहलेपहल यह मामला मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीबीआइ) की अदालत में आया. वहां से विशिष्ट न्यायाधीश, सीबीआइ मामलात की अदालत में. यहां से इसका फिर तबादला हुआ और यह सत्र न्यायाधीश, जयपुर की अदालत में आया. अब यह अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (शहर) की अदालत में है जिसे उच्च न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय का दर्जा दे रखा है. अभी इस मामले में आरोपों पर सुनवाई का वक्त नहीं आया है. अधिकांश पेशियों पर अभियुक्तों की ओर से अर्जियां पेश हुई हैं जिनमें मामले से संबद्ध रिकार्ड को देखने की मांग की गई है. पिछली पेशी 20 फरवरी को थी. उस पेशी पर भी इसी तरह की ही एक अर्जी आई थी.

अभियुक्तों के कटघरे में हैं डीग के निलंबित उप पुलिस अधीक्षक कान सिंह भाटी, डीग थानाधिकारी वीरेंद्र सिंह और 16 जवान. सीबीआइ ने इनके खिलाफ चालान पेश किया है कि डीग थाने में 20 फरवरी 1985 को दो एफआइआर दर्ज हुई थीं. इनमें शिकायत की गई थी कि राजा मानसिंह ने अपने 'वैपन कैरियर' से टक्कर मार कर मुख्यमंत्री माथुर का हैलीकॉप्टर ध्वस्त कर दिया. राजा ने वह मंच भी तोड़ दिया जिस से माथुर कांग्रेस की चुनाव सभा को संबोधित करने वाले थे.

चालान में आगे कहा गया है कि कान सिंह भाटी को 21 फरवरी को तीन टेलीफोन संदेश मिले जिसके बाद वे पुलिस बल लेकर डीग की अनाज मंडी की तरफ चले. यहां राजा मान सिंह अपनी चुनाव सभा में भाषण देने आने वाले थे. भाटी ने उन्हें रुकने का इशारा किया. राजा ने अपना वैपन कैरियर पीछे किया और इशारा किया कि वे आगे रोक रहे हैं. लेकिन भाटी ने बिना किसी कारण के मानसिंह पर गोली चला दी और अपने साथियों से भी गोली चलाने को कहा. इसमें मानसिंह व उनके दो सहयोगी मारे गए.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

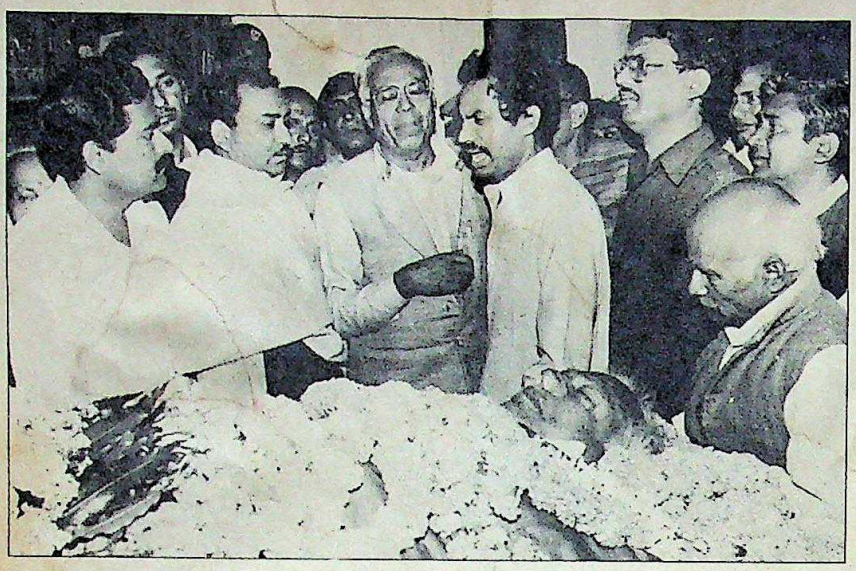

कर्पूरी ठाकुर

जननेता का निधन

विपक्षी एकता मंझधार में

लोकदल (ब) के नेता 68 वर्षीय कर्पूरी ठाकुर के अचानक निधन से बिहार में विपक्षी ताकतों की स्थिति बिन पतवार नैया जैसी हो गई है और वे असमंजस में फंस गई हैं. पिछड़ी जातियों और दूसरे कमजोर वर्गों में कर्पूरी का व्यापक जनाधार था और 17 फरवरी को दिल के दौरे से मृत्यु से पहले तक वे विपक्षी दलों की एकता के प्रयास में जुटे हुए थे.

डॉ. राममनोहर लोहिया के निधन के बाद कर्पूरी समाजवादी आंदोलन के प्रतीक बन गए थे और चौधरी चरण सिंह की मौत के बाद तो उन्हें पिछड़े वर्गों का बेताज बादशाह माना जाने लगा था. तीन महीने पहले विपक्षी पार्टियों की 'न्याय रैली' में उन्हें 'आशा की एकमात्र किरण' बताया गया था. उस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री देवीलाल ने उन्हें हरी पगड़ी पहनाई थी और जनता को इंका के खिलाफ जगाने के लिए 'न्याय रथ' भेंट किया था.

पटना में उनके अंतिम संस्कार के दिन शोकसंतप्तों की विशाल भीड़ ही लोगों के दिल में उनके प्रति गहरी श्रद्धा को प्रदर्शित कर रही थी. अपने व्यक्तित्व के बल पर कर्पूरी ने जातिगत विवादों के लिए मशहूर और राजनैतिक रूप से संवेदनशील इस राज्य में अपने दल के कई गुटों को एक सूत्र में पिरोए रखा था.

अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने देश भर के विपक्षी नेता पटना आए. इनमें से एक का कहना था, "कर्पूरी जी का एकमात्र विकल्प विपक्षी एकता ही हो सकती है." जनता पार्टी के नेता मधु दंडवते ने कहा, "उनके चलाए गए एका अभियान को हमें आगे बढ़ाना है." विपक्षी एकता के प्रयासों में कर्पूरी का साथ देने वाले और इस सवाल पर जनता पार्टी के अपने नेतृत्व से मतभेद रखने वाले जार्ज फर्नांडीस ने अब उनके इस मिशन को सिरे चढ़ाने का फैसला किया है.

लेकिन राज्य में जनाधार वाले एकमात्र विपक्षी नेता कर्पूरी के अभाव में एकता का प्रयास काफी कठिन सिद्ध होगा. वे विपक्षी नेताओं को एक मंच पर लाने में निर्णायक भूमिका निभा रहे थे. मौत के कुछ हफ्ते पहले ही उन्होंने उत्तर भारत में इंका विरोधी आंदोलन चलाने की रणनीति पर विश्वनाथ प्रताप सिंह से विचार-विमर्श किया था. उन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह समेत समस्त गैर-कम्युनिस्ट विपक्षी पार्टियों को करीब-करीब मना लिया था कि विपक्षी गठबंधन में भाजपा को शामिल करना जरूरी है क्योंकि हिंदी क्षेत्र में उसकी भी लोकदल (ब) के बराबर ही ताकत है. भाजपा को साथ लेने का मुद्दा विपक्षी एकता की राह में रुकावट बना हुआ था.

कर्पूरी भले ही राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता के प्रयास में लगे थे पर अपने गृह-राज्य में कुछ शक्तिशाली पिछड़े वर्ग उनसे दूर भी हटते जा रहे थे. लोकदल (अ) के साथ इन वर्गों की नजदीकियां बढ़ने लगी थीं. अंतिम संस्कार के मौके पर अजीत सिंह ने अपने समर्थकों को एकता प्रयास चलाने के संकेत दिए भी ताकि स्थिति का फायदा

ठाकुर के बेटे को मुख्यमंत्री की सांत्वना

उठाया जा सके. लेकिन उत्तर प्रदेश लोकदल (ब) के नेता मुलायम सिंह यादव इसका विरोध करने में लगे हैं. जेपी विचार मंच के सरयू राय के अनुसार जेपी आंदोलन के कार्यकर्ता अब एक हो रहे हैं.

उधर इंकाई हलकों में भी चिंता झलकने लगी है. पार्टी के बहुत से नेताओं को आशंका है कि कर्पूरी के निधन से सरकार के खिलाफ राज्य के पिछड़े वर्गों का गुस्सा भड़क उठेगा. विधानसभा अध्यक्ष शिवचंद्र झा ने पिछले साल अगस्त में अपने एक विवादास्पद फैसले द्वारा कर्पूरी को विपक्षी नेता के पद से वंचित कर दिया था. इंका नेता मानते हैं कि इस कार्रवाई से पिछड़े वर्ग, जिनकी राज्य में 60 फीसदी आबादी है, एक मंच पर आ गए हैं और कर्पूरी के निधन से अब उनका असंतोष नई रंगत दिखा सकता है.

—फरजंद अहमद

फार्म IV (नियम 8 देखें)

1.	प्रकाशन का स्थान	: नई दिल्ली
2.	प्रकाशन की आवर्तिता	: पाक्षिक
3.	मुद्रक का नाम	: अरुण पुरी
	क्या भारतीय नागरिक हैं? (अगर विदेशी हों, तो मूल देश का नाम)	: हां : लागू नहीं
4.	प्रकाशक का नाम	: अरुण पुरी
	क्या भारतीय नागरिक हैं? (अगर विदेशी हों, तो मूल देश का नाम)	: हां : लागू नहीं
	पता	: लिविंग मीडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, के-ब्लॉक, कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001
5.	संपादक का नाम	: अरुण पुरी
	क्या भारतीय नागरिक हैं? (अगर विदेशी हों, तो मूल देश का नाम)	: हां : लागू नहीं
	पता	: के-ब्लॉक, कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001
6.	उन लोगों के नाम और पते जो: मालिक समाचार पत्र के मालिक हों, या जिनके पास कुल पूंजी का एक फीसदी से अधिक हो.	लिविंग मीडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, के-ब्लॉक, कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001

कुल पूंजी में एक फीसदी से अधिक की हिस्सेदारी रखने वाले शेयरहोल्डरों के नाम और पते:

1. श्री अरुण पुरी, ए-6, पालम मार्ग, वसंत विहार, नई दिल्ली.
2. श्रीमती रेखा पुरी, ए-6, पालम मार्ग, वसंत विहार, नई दिल्ली.
3. मास्टर अंकुर पुरी, (नाबालिग), ए-6, पालम मार्ग, वसंत विहार, नई दिल्ली.
4. श्रीमती मंदिरा पुरी, फावलेट, 5, कार्लो एवेन्यू, नेपियन, ओंतारियो के-2, जी.ओ.पी. 9, कनाडा.
5. श्रीमती मधु ग्रेहन, सी-19 माल्वा मार्ग, नई दिल्ली.
6. द ऑल इंडिया इंवेस्टमेंट कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, के-ब्लॉक, कनाट सर्कस, नई दिल्ली.
7. एल. एम. डिस्ट्रिब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, के-ब्लॉक, कनाट सर्कस, नई दिल्ली.

मैं, अरुण पुरी घोषित करता हूं कि ऊपर दिए गए ब्यौरे मेरी जानकारी और मान्यता के अनुसार सही हैं.

दिनांक: 1 मार्च, 1988

हस्ता. अरुण पुरी
प्रकाशक के हस्ताक्षर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

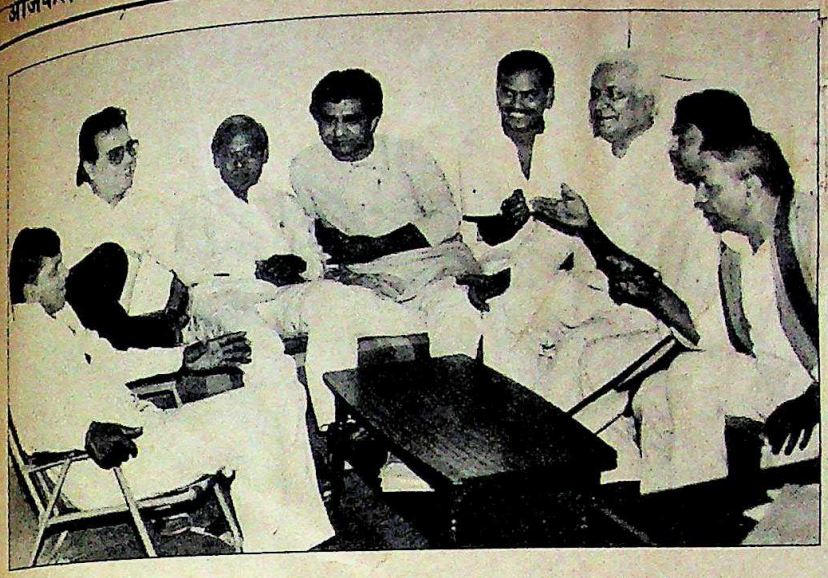

इंकाई असंतुष्टों की बैठक

गुजरात

बदलाव के बादल

सत्ता पार्टी में असंतोष बढ़ा

बदलाव की इच्छा निश्चय ही संक्रामक होती है. राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश के नेतृत्व परिवर्तन से गुजरात के इंका असंतुष्टों के बुलंद हुए हौसले तो यही संकेत देते हैं. असंतुष्टों ने 'पार्टी के हित में' मुख्यमंत्री अमरसिंह चौधरी को हटाने के लिए पिछले पखवाड़े हस्ताक्षर अभियान छेड़ दिया.

असंतुष्ट सही अवसर की ही ताक में थे. मार्च में राज्यसभा की चार सीटों के लिए होने वाले चुनाव के रूप में उन्हें यह मौका मिल गया है. राज्य के इंका नेताओं में चौधरी के एकमात्र पक्षधर केंद्रीय इस्पात राज्यमंत्री योगेंद्र मकवाना के भड़काऊ भाषण ने भी चिंगारी का काम किया. मकवाना ने हरिजनों और वनवासियों को दूसरे पिछड़े वर्गों के विरुद्ध भड़काया था.

ये विद्रोही बेहद सावधानी से तैयार की गई रणनीति के अनुसार काम कर रहे थे. प्रमुख असंतुष्ट विधायक जितेंद्र शाह और दिगंत ओझा हालांकि कहते हैं कि यह अभियान स्वयंस्फूर्त है. लेकिन इस बात में जरा भी संदेह नहीं कि असंतुष्टों को औरों के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी का समर्थन प्राप्त है.

मुख्यमंत्री के खिलाफ असंतोष की आग अरसे से सुलग रही है. चौधरी मंत्रिमंडल का विस्तार करना चाहते थे लेकिन राजीव गांधी ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी. नतीजतन चौधरी सूखाग्रस्त राज्य का काम-काज ग्यारह सदस्यों के 'मिनी मंत्रिमंडल' से ही चलाने को मजबूर हैं. चौधरी पर दो मुख्य आरोप हैं—एक तो यह है कि प्रशासन पर उनकी पकड़ कमजोर है. दूसरे यह कि वे विपक्ष के साथ मेलजोल रखते हैं.

यह ठीक भी है. चौधरी का व्यक्तित्व सोलंकी जैसा चमत्कारी और गतिशील नहीं है लेकिन सोलंकी की वजह से पार्टी को भारी नुकसान भी पहुंचा था. पिछड़े वर्ग के हित को ध्यान में रखकर बनाई गई सोलंकी की नीतियों का एकमात्र उद्देश्य वोट बटोरना ही था. उनकी इन नीतियों के कारण ही गुजरात का सामाजिक ढांचा दरक गया था. सोलंकी के उथल-पुथल भरे शासनकाल के बाद चौधरी को राज्य में शांति स्थापित करने का श्रेय तो दिया ही जाना चाहिए.

राज्य में आजकल राजनैतिक तराजू इस कदर पिछड़े वर्ग के पक्ष में झुक गया है कि सत्तारूढ़ पार्टी के उच्च स्तर पर दूसरे तबकों का प्रतिनिधित्व न के बराबर है. खुद चौधरी वनवासी हैं, गुजरात से दोनों केंद्रीय मंत्री मकवाना और वित्त राज्यमंत्री बी.के. गाधवी पिछड़े वर्ग से हैं.

हालांकि इंका महासचिव गुलाम नबी आजाद ने दिल्ली में ऐलान तो किया है कि गुजरात में फिलहाल नेतृत्व परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है. लेकिन पहले ऐसे बयानों के बावजूद कुछ मुख्यमंत्री हटाए जा चुके हैं. पर चौधरी वनवासी हैं इससे पार्टी दावा कर सकती है कि वह कमजोर तबकों की पक्षधर है. लेकिन आलाकमान के मूड की कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती.

—उदय माहूरकर

चंद्रास्वामी

फंदे में फंसे गुरु

सरकार आसानी से नहीं छोड़ेगी

पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाले गुरु चंद्रास्वामी की कड़ी घेराबंदी कर दी गई है. वे विदेश नहीं जा सकते. गिरफ्तार होने का खतरा मोल लिए बिना वे अपने नर्सिंग होम से भी बाहर नहीं निकल सकते. 13 फरवरी को सीबीआई ने उन्हें उनके सहयोगी कैलाशनाथ अग्रवाल के साथ गिरफ्तार किया था और फिलहाल

प्रमोद पुष्करणा

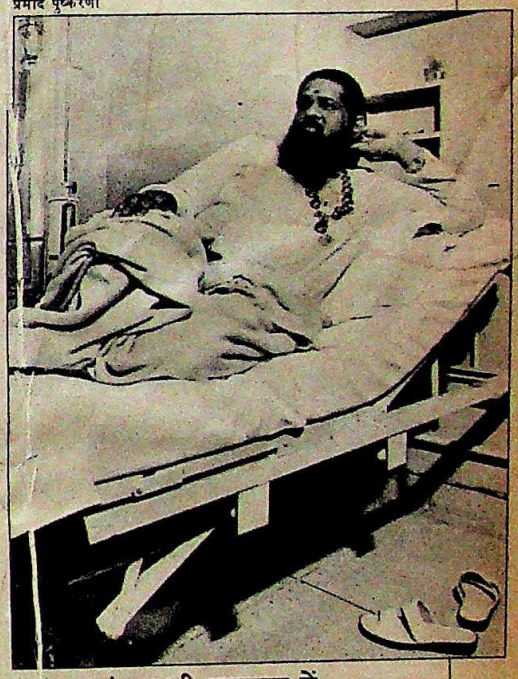

चंद्रास्वामी अस्पताल में

चंद्रास्वामी जमानत पर छूटे हुए हैं.

केवल सीबीआई ही उनके खिलाफ जांच नहीं कर रही है. प्रवर्तन निदेशालय पिछले सितंबर से उनके खिलाफ विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन के मामलों की जांच कर रहा है. पिछले पखवाड़े आयकर अधिकारियों ने अग्रवाल के घर पर छापा डाला. स्वामी ने पिछले अक्तूबर से विपक्षी दलों का पक्ष ले लिया है. इस कारण भी सरकार उनसे हिसाब-किताब निबटा लेने को उतारू दिखती है. उनके वकील राम जेठमलानी ने कहा, "साफ है कि सरकार उन सभी को धमकाना और परेशान करना चाहती है जिन पर विरोधी होने का शुबहा हो."

आशंका यह है कि चंद्रास्वामी अपने धन से विपक्षी दलों की मदद कर सकते हैं.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

चंद्रास्वामी गर्व से यह बताते भी रहे हैं कि उनके कुछ अनुयायी संसार के सबसे अमीर और प्रसिद्ध व्यक्ति हैं. इनमें वे बूनी के सुल्तान और हथियारों के बड़े सौदागर अदनान खाशोगी का नाम लेते हैं.

जो लोग उनसे आध्यात्मिक अथवा दूसरी सहायता लेने आते हैं उनमें मार्टिन अर्डबो भी हैं. वे उस समय स्वीडिश बोफोर्स कंपनी के अध्यक्ष थे जब उसने भारत को होविट्जर तोपों की सप्लाई के ठेके के लिए कथित घूस दी थी. पिछले मार्च में 'इंडियन एक्सप्रेस' के मालिक रामनाथ गोयनका के दिल्ली स्थित अतिथिगृह में सीबीआई ने जब छापा मारा था तो वे वहां पाए गए थे. इसलिए संदेह है कि उन्हें इस सौदे की काफी जानकारी है.

उनकी गिरफ्तारी के बाद जैन मेडिकल सेंटर में 'एक्सप्रेस' के संपादक अरुण शौरी और गोयनका के सलाहकार एस. गुरुमूर्ति उनके पलंग के पास खड़े थे. सीबीआई द्वारा उनके घर की तलाशी का वारंट पाने के दूसरे दिन 9 फरवरी को उन्हें इस नर्सिंग होम में दाखिल किया गया था.

चंद्रास्वामी के चिंतित होने के पर्याप्त कारण हैं. सूत्रों के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय को उनके खिलाफ पर्याप्त प्रमाण मिल गए और वह अगले महीने तक कानूनी कार्रवाई करने की योजना बना रहा है. इस बीच सीबीआई न केवल धोखाधड़ी के आरोपों बल्कि चंद्रास्वामी के खिलाफ नए मामले दर्ज कराने की भी कोशिश कर रही है. इंटरपोल की मदद ली जा रही है.

सूत्रों के अनुसार सीबीआई को चंद्रास्वामी की धोखाधड़ी का एक शिकार स्पेन में और एक अमेरिका में भी मिल गया है. बताया जाता है कि एक मामले में चंद्रास्वामी और अग्रवाल ने किसी लखूभाई पटेल को भारत में लुगदी सप्लाई का ठेका दिलाने का वायदा किया और 13 लाख रुपए ऐंठ लिए. पटेल के अनुसार चंद्रास्वामी ने उन्हें विश्वास दिला दिया था कि भारत में उनकी ऊपर तक पहुंच है.

बहरहाल, चंद्रास्वामी ने अस्पताल के बिस्तर से ही सरकार के साथ चूहे-बिल्ली का खेल खेलने का निश्चय कर लिया लगता है. जबकि सरकार उनके इस डर से यह खेल खेल रही है कि वे बोफोर्स मामले में काफी रहस्य जानते हैं. स्वामी ने घोषणा भी कर दी है, "सही वक्त आने पर मैं वह सब कहूंगा जो मैं कहना चाहूंता हूं." लेकिन जब तक सही समय नहीं आता तब तक तो लगता है उनकी पर्याप्त खिंचाई होती रहेगी.

—डेविड देवदास

पंजाब

फिर गरम तेवर

उग्रवाद को समर्थन

सिख उग्रवादियों को पिछले पखवाड़े उस समय एक कामयाबी हाथ लगी जब लुधियाना में एकीकृत अकाली दल की 25,000 लोगों की विशाल रैली में अतिवादी हो-हल्ले के आगे उदार स्वर दब गए. पहले की तरह इस बार उग्रवादियों को मंच हथियाने की जरूरत नहीं पड़ी. क्योंकि एकीकृत अकाली दल के नेता स्वेच्छा से उनकी तरफ हो गए.

अमरिंदर और बादलः अलग रास्ते

छह घंटे की इस रैली में जरनैल सिंह भिंडरांवाले का असर ही छाया रहा. इस असर को वश में किए हुए थे भिंडरांवाले के पिता बाबा जोगिंदर सिंह, सेना से अवकाश के बाद एकीकृत अकाली दल में शामिल उनके भतीजे हरचरण सिंह रोडे और इंदिरा गांधी के हत्यारे सतवंत सिंह के पिता तरलोक सिंह. एक सजी-संवरी पालकी में रखे गुरु ग्रंथ साहिब वाले पवित्र पालकी में उन्होंने भिंडरांवाले का रास्ता अख्तियार करने की शपथ ली.

इस सभा से पार्टी की गुटबाजी भी साफ हो गई है. एकीकृत अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल और सुखजिंदर सिंह ने उग्रवादियों के विचारों को स्थान देने के लिए आखिरी मौके पर पार्टी प्रस्ताव में फेरबदल किया.

पूर्व मुख्यमंत्री बादल अब उग्रवादियों को करीब लाने के लिए नया रुख अख्तियार कर रहे हैं. असल में उग्रवादियों को उन पर अभी भी भरोसा नहीं हो पाया है.

संशोधित प्रस्ताव में उग्रवादियों का समर्थन ही नहीं किया गया है बल्कि उन्हें महिमामंडित भी किया गया है. इसमें कहा गया है: "अपने इतिहास, परंपरा और गौरव को कायम रखते हुए सिखों ने प्रतिरोध के अनोखे तरीके अपनाए हैं." इसके अलावा किसी भी नेता ने उग्रवादियों द्वारा निर्दोष लोगों की अंधाधुंध हत्याओं की चर्चा तक नहीं की. लेकिन प्रायः सभी ने फर्जी पुलिस मुठभेड़ों में सिख युवकों के मारे जाने की एक स्वर से निंदा की.

रैली में इस धारा से असहमति व्यक्त करने वाले पटियाला राजघराने के अमरिंदर सिंह ने कहा कि सिखों का आंदोलन अहिंसक होना चाहिए.

उग्रवाद को न्यायोचित बताकर बादल उग्रवादियों के करीब आ गए पर अमरिंदर का झुकाव बरनाला की ओर ही है

अमरिंदर सिंह के साथ एकीकृत अकाली दल के 22 विधायक हैं. ये सभी समझौते की भावना का समर्थन करते हैं और इसकी विफलता के लिए दिवंगत हरचंद सिंह लोंगोवाल को दोषी नहीं मानते. लेकिन एकीकृत अकाली दल के बाकी विधायक समझौते के साथ ही दोनों पक्षों को समान रूप से त्याज्य मानते हैं.

वैचारिक तौर पर अमरिंदर सिंह समझौते के अमल के तौर-तरीके पर अकाली दल (लोंगोवाल) के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री सुरजीत सिंह बरनाला के ज्यादा नजदीक हैं. इसके साथ ही महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अपने विरोध सुलटाने के लिए अमरिंदर सिंह और बरनाला पिछले कई हफ्तों से चुपचाप मिल रहे हैं. यह नया गठजोड़ अगर उभरता है तो इससे उग्रवादियों के पक्षधर बादल के दल के लिए सशक्त विरोध खड़ा हो सकता है. —विपुल मुद्गल, लुधियाना से

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जीनियस का बजट

अब तो इस रहस्य पर से परदा उठाया ही जा सकता है. कुछ सप्ताह पहले केंद्रीय वित्तमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने मुझसे मिलने का समय मांगा. मुझे भला क्या आपत्ति हो सकती थी. मैंने उन्हें समय दे दिया.

वे नियत समय पर आए कुछ परेशान-से, उलझन में डूबे हुए. कहने लगे, "मुझे आपकी सहायता चाहिए. बजट पूरी तरह अस्त-व्यस्त पड़ा है. और मुझे सूझ ही नहीं रहा कि क्या करना चाहिए. अब तो कोई जीनियस ही इस देश की अर्थ-व्यवस्था को बचा सकता है."

मैंने पूछा, "लेकिन यह तो बताइए असली समस्या क्या है?"

हताश-से स्वर में वे बोले, "हमारे स्रोत समाप्त हो चुके हैं."

मैंने झिड़कते हुए कहा, "तकनीकी शब्दों का चक्कर छोड़ो. सीधी-सीधी बात करो. तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारे पास पैसा नहीं रहा! भाई तुम पहले की ही तरह उद्योगपतियों, व्यापारियों, निश्चित आमदनी वाले कर्मचारियों और जनता से बजट की जरूरतों के लिए पैसा क्यों नहीं वसूलते?"

वे बोले, "हम उन्हें पहले ही अच्छा-खासा निचोड़ चुके हैं. अब उन बेचारों के पास बचा ही नहीं कि कुछ वसूला जा सके. जिनके पास बचा था उन्होंने जब से अपना पैसा स्विस बैंकों में जमा कराना शुरू किया तब से देश में पैसे की भयंकर किल्लत हो गई है."

मैंने कहा, "ठीक है. मैं तुम्हारी मदद करूंगा. मैं एक छापेखाने का पता बताता हूं जो तुम्हें तुम्हारी जरूरत का पैसा मुहैया करा देगा."

तिवारी की आंखें कृतज्ञता के आंसुओं से डबडबा गईं. वे कहने लगे, "तुमने मेरी जान बचा ली. अब तो केवल टैक्स लगाना बाकी है और बस, बजट तैयार. लेकिन असली मुश्किल तो यह है कि शुरुआत कैसे की जाए?"

मैंने कहा, "मेरे ख्याल से वक्त आ गया है कि देश को एक असली क्रांतिकारी बजट मिले. इसलिए उन लोगों पर टैक्स न लगाया जाए जिनके पास देने के लिए पैसा नहीं है. टैक्स उन पर लगाया जाए जो इसे अदा कर सकें."

तिवारी ने उत्सुकता से पूछा, "तुम कहना क्या चाहते हो?"

मैंने मामला साफ करते हुए कहा, "अरे भाई असली कमाल तो छापेखाने का है. इसकी वजह से केवल सरकार के पास ही अतिरिक्त धन होगा. इसीलिए

क्यों न इस बार सारा टैक्स सरकार ही अदा करे?"

वे इस अर्थ-गणित को समझ नहीं पाए. पूछ बैठे, "सरकार का काम तो टैक्स वसूलना होता है. भला वह खुद टैक्स क्यों दे? और फिर वह किसे देगी यह टैक्स?"

मैंने शांत भाव से कहा, "जनता को, और किसे! चालीस साल से जनता सरकार को टैक्स अदा कर रही है. इस बार क्यों न बदलाव के तौर पर सरकार टैक्स अदा करे? सरकार को जितनी जरूरत है वह उतने नोट छापेखाने में छाप ले और जनता को टैक्स के नाम पर अदा कर दे."

इस सुझाव की बारीकियों को समझने के लिए तिवारी कुछ देर के लिए विचार-मग्न हो गए. मन ही मन कुछ जोड़-घटाव करने के बाद वे शांत हो गए. फिर बोले, "मैं तुम्हारा सुझाव ठीक तरह से समझ नहीं पा रहा. सरकार अपने कार्यक्रमों के लिए जनता से टैक्स वसूलती है. अगर मान भी लिया जाए कि वह अपनी जरूरत का पैसा तुम्हारे इस छापेखाने से ले सकती है तो भी भला जनता को टैक्स क्यों अदा किया जाए? और फिर सरकार से ये टैक्स लेकर बदले में जनता करेगी क्या?"

मैंने कहा, "जनता भी वही कार्य करेगी जो आज सरकार करने की कोशिश कर रही है. वह कानून और व्यवस्था लागू करेगी, राजस्व वसूली करेगी, परिवहन और दूसरी व्यवस्थाओं को संभालेगी. वास्तव में कई लोगों ने ऐसा करना शुरू भी कर दिया है. अब महेंद्र सिंह टिकैत को देखो, गांवों में न्याय व्यवस्था संभाले हुए हैं. धनबाद कोयला खदानों में यूनियन के नेताओं को देखो जो लोगों से राजस्व वसूलते हैं. बिना टिकट बसों और ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को देखो, वे सरकारी परिवहन व्यवस्था को संभाले हैं. इन लोगों की सेवाओं की कीमत क्या अदा नहीं की जानी चाहिए?"

तिवारी फिर शांत हो गए. कुछ देर बाद बोले, "पर अगर जनता खुद ही यह सब करने लगी तो सरकार के पास करने के लिए कुछ भी नहीं रह जाएगा?"

मैंने विजेता के अंदाज में जवाब दिया, "बिलकुल सही कहा. तब सरकार एकदम लुप्त हो जाएगी! यही तो है समाजवाद का असली लक्ष्य. क्यों सही है न?"

तिवारी ने तपाक से हाथ मिलाया और जाते-जाते कहा, "भाई, तुम वाकई जीनियस हो." लेकिन आप सबने देखा होगा कि इस सबके बावजूद बजट वैसा नहीं था जैसी मैं उम्मीद लगाए था. समझ नहीं आ रहा कि गलती आखिर हुई कहां.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

महेंद्र सिंह टिकैत

एक लौहपुरुष का उद्भव

बिना कुछ लिए धरना खत्म करने के बावजूद किसानों की ताकत बढ़ी

मेरठ में मंडल आयुक्त के दफ्तर के आसपास धूल उड़ाती भीड़ रवाना हो चुकी है और पास के मैदान पर गड़े तंबू भी उखाड़कर ले जाए जा चुके हैं. आयुक्त के दफ्तर पर महेंद्र सिंह टिकैत के किसानों की फौज के 25 दिन के घेरे की निशानी की बतौर अब कुछ पुआल और कूड़ा-करकट ही रह गया है. यह घेराव सिर्फ आयुक्त के दफ्तर का नहीं था, लखनऊ और दिल्ली की सरकारें भी इससे थर्रा उठी थीं. राजीव गांधी ने जब टिकैत के भारतीय किसान यूनियन (बीकयू) की सारी मांगें ठुकरा दीं तो यह धरना उठ गया और उत्तर प्रदेश सरकार यह मानकर फूले नहीं समाई कि टिकैत ने आखिरकार हार मान ली.

धरना तो उठ गया पर इसको आयोजित करने वाले टिकैत का कद और ऊंचा हो गया है. अब सभी उनका लोहा मानेंगे. ठेठ देहाती और बमुश्किल साक्षर इस जाट किसान ने चौधरी चरण सिंह जैसा रंग-ढंग अपनाया और देश के किसान नेताओं के दुर्ग पर अपना झंडा फहरा दिया. पड़ोसी राज्य हरियाणा में देवीलाल की जैसी हवा चली थी, वैसी ही हवा इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी चली, इस तूफान की अगुआई टिकैत कर रहे थे. फर्क सिर्फ यही है कि टिकैत अभी तक परंपरागत अर्थों में 'नेता' नहीं बने हैं.

फिर उन्होंने धरना वापस क्यों लिया? अगर टिकैत राजनैतिक नेता होते तो उनका अहं और बाद में वोटरों के रवैये की चिंता उन्हें ऐसा नहीं करने देती. मेरठ में जुटे लाखों लोग उनके आदेश से कुछ भी कर सकते थे. हिंसा भी फैला सकते थे. कुछ गुस्से और विक्षोभ से भरे दाहा गांव के बूढ़े किसान रामसरूप ने कहा कि चौधरी टिकैत के कहने भर की देरी थी, वे लोग पुलिस की गोलियां खाने को तैयार थे. ऐसे रामसरूपों की कमी नहीं थी. रामसरूप ने कहा, "यह सरकार हमारी बात नहीं मानती. हमें तो वैसे भी मरना है." और यह कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए. मुजफ्फरनगर जिले के आलम गांव के सुखवाल सिंह पंवार ने और स्पष्ट तरीके से कहा, "अगर टिकैत कहेंगे कि अपनी फसलें जला दो, रेलवे लाइन उखाड़ दो

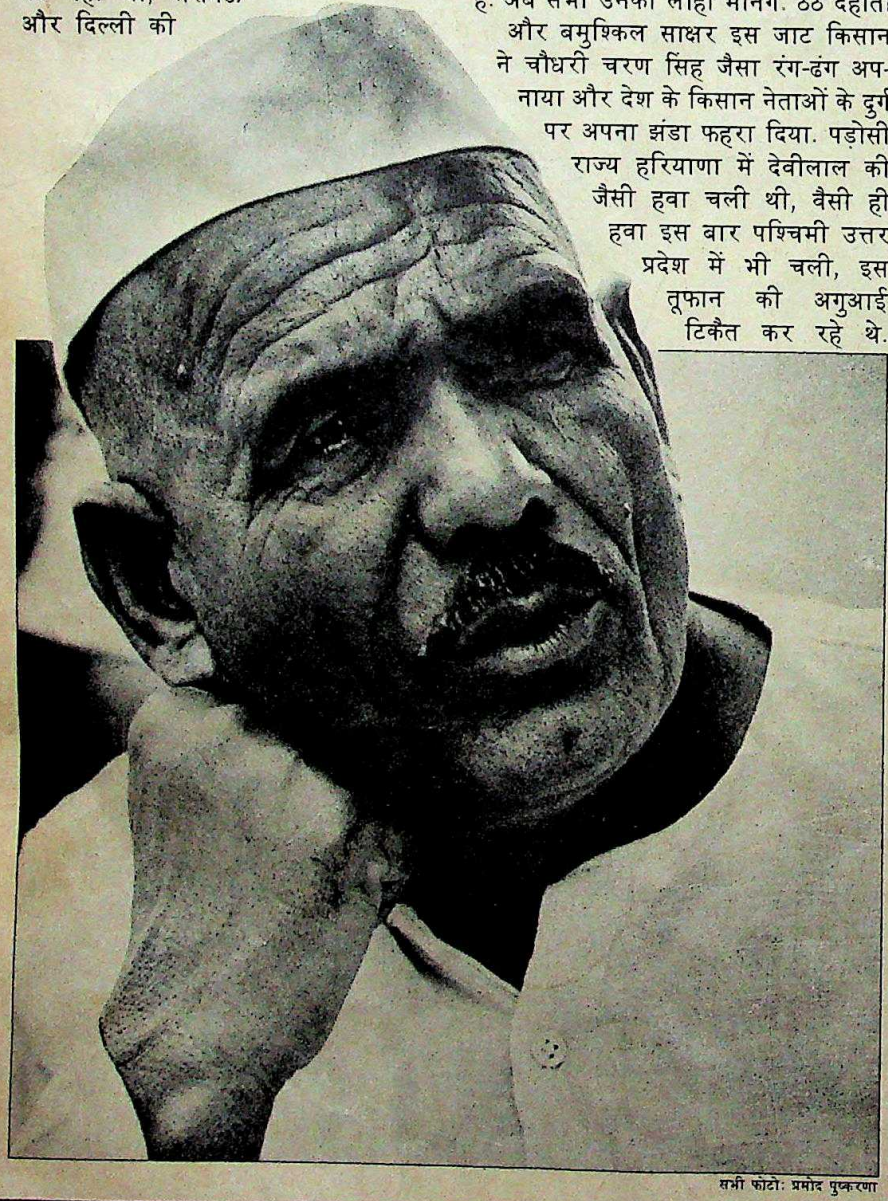

सभी फोटो: प्रमोद पुष्करणा

बातचीत

'किसान अब चुपचाप नहीं बैठेंगे'

दुबले-पतले और ऊंचे महेंद्र सिंह टिकैत की हस्ती बुलंद है. किसानों के हक के लिए सरकार से सीधे भिड़ गए टिकैत बगैर मैदान से हटेंगे, इसकी संभावना नहीं लगती. विशेष संवाददाता रमिंदर सिंह को [illegible] *प्राथमिक स्कूलों की भग्न इमारतों और अपने गांव का स्वास्थ्य केंद्र दिखाते वक्त उन्होंने अपना गुस्सा भी दिखाया. गुस्से में अपना एक जूता ही निकाल लिया. पर राज्य के किसानों के इस 53 वर्षीय 'देवता' का यह रूप बताता है कि वे सरकार और उसकी एक पक्षीय नीति से नाराज होकर उससे भिड़ गए हैं. मेरठ में 25 दिनों के धरने के बाद आराम करके तरोताजा लग रहे टिकैत ने 'इंडिया टुडे' से बातचीत की. उसके अंश:*

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अपने गांव के स्कूलों की खस्ता हालत भी टिकैत को आंदोलन के लिए उकसाती है

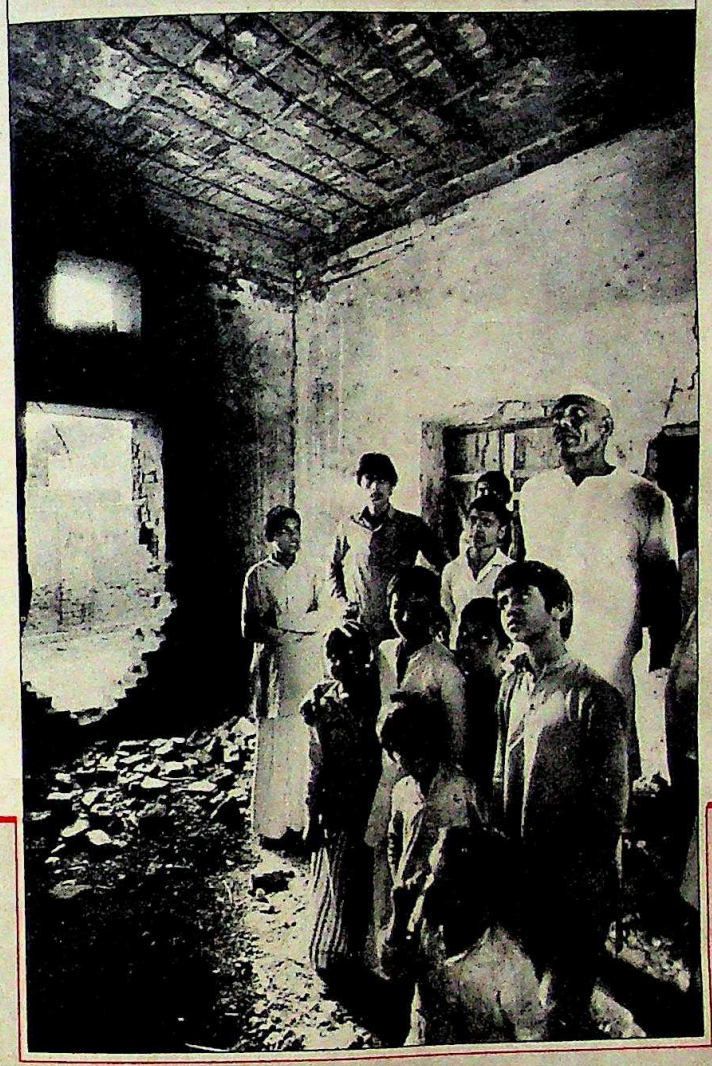

और गाड़ियों का आना-जाना रोक दो, तो हम यह भी करेंगे. पुलिस की गोली खाकर मरना सरकार के सामने हाथ पसारने से कहीं बेहतर है."

बाहर से भले ही लगता है कि टिकैत ने पीठ दिखा दी हो पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट-बहुल इलाके में उनका समर्थन कम नहीं हुआ है. कुछ धूम-धड़ाका न होने से मुट्ठी भर नौजवान जरूर निराश हुए पर अधिकांश किसानों का मानना है कि कुछ सोचकर ही 'महात्मा' टिकैत ने यह फैसला लिया है. मेरठ जिले के कंडला के पास रामवाला सहकारी चीनी मिल के सामने गन्ने की गाड़ी लगाए खड़े किसानों में से सिर्फ एक ही समूह का मानना था कि हिंसा होती तब भी धरना जारी रखना चाहिए था. नाला गांव के सुरिंदर सिंह ने कहा, "सरकार कभी भी शांति से मांगें नहीं मानती." बाकी सभी लोगों का मानना था कि टिकैत ने अच्छा ही किया. बराल गांव के मौजी राम ने कहा कि गन्ने की फसल अभी खेत में पड़ी है और उसी के नुकसान को ध्यान में रखते हुए टिकैत ने आंदोलन वापस ले लिया.

लेकिन अप्रैल में गेहूं की फसल कटने के बाद मामला तूल पकड़ेगा. मौजी राम ने कहा कि वह और उनके जैसे और लोग मौजूदा दर पर अपना गेहूं सरकारी एजेंसियों को और बाजार में नहीं बेचेंगे.

आंदोलन जारी रखने के लिए भारतीय किसान यूनियन ने जिन कदमों की घोषणा की है उनमें से गेहूं नहीं बेचना भी एक है. जब मेरठ का धरना खत्म हुआ तो टिकैत ने किसानों को कई और निर्देश दिए. इनमें बिजली के बिल न देना, मकान का टैक्स या लगान न देना और किसी भी सरकारी मुलाजिम को गांव में घुसने न देना शामिल है. कुछ चीजों का बहिष्कार तो अभी से शुरू भी हो चुका है. खुद टिकैत ने पिछले 25 महीनों का अपना बिजली का बिल नहीं दिया है. राज्य बिजली बोर्ड के रिकार्डों से पता

• आपने धरना क्यों उठा लिया?

कई कारण थे. पहला तो भगवान का डर था. मेरे बुलावे पर काफी लोग मेरठ में जमा हो गए थे. खतरा था कि मुझमें अहंकार न आ जाए. फिर मेरठ के विद्यार्थियों की चिंता थी. इम्तहान पास आ रहे थे और धरने के कारण स्कूल-कॉलेज बंद पड़े थे. और फिर भारतीय किसान यूनियन के वेश में कुछ लोग हिंसा और तोड़फोड़ करने लगे. हमें शहर में फैलती वहशी और किसानों पर पड़ रहे मेरठ शहर के गलत असर की भी चिंता थी.

• आगे की क्या योजना है?

पहले तो चार-पांच दिन आराम करना है. उसके बाद फिर मैदान में उतरेंगे. अगर सरकार का रुख सहानुभूतिपूर्ण नहीं हुआ तो हम लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे. किसान मेरठ से बाहर आ गए हैं, इसलिए सरकार को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि वह जीत गई है. किसान यूनियन का भूत उस पर रोज मंडराएगा.

• आप अक्सर कहा करते थे कि कुछ मांगें मनवाए बिना मेरठ से हटेंगे ही नहीं.

लखनऊ में राजीव गांधी के भाषण से स्पष्ट हो गया कि हमें कोई रियायत नहीं मिलने वाली. अगर हमारा धरना दो हफ्ते और चलता तो दो बातें हो सकती थीं. हमारा संगठन तो मजबूत होता लेकिन धरने से हिंसा और तोड़फोड़ शुरू हो जाती.

• 35 मांगों में से कौन-सी ऐसी मुख्य मांगें हैं जिन्हें आप मानने पर जोर देते हैं?

शिक्षा की सुविधा, खेती के उत्पादनों की उचित कीमत (जिसमें चीनी के उत्पादन के हिसाब से गन्ने का दाम शामिल है) और जहां जरूरी हो वहां सूखा राहत कार्यक्रम. हम जानते हैं कि भ्रष्ट अधिकारी एक तक नकद राहत नहीं आने देंगे. इसलिए सरकार बिजली के बिल माफ करे.

• राज्य सरकार मानती है कि धरना उठाकर आपने हार मान ली.

किसान जानते हैं कि प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए. राजीव ने लखनऊ में कहा कि उन पर दबाव नहीं चल सकता. क्या सरकार ने पिछली अप्रैल में दबाव से बिजली की दर में 7.50 रुपए की कमी नहीं की थी? प्रधानमंत्री नादिरशाह की तरह बोलते हैं. क्या उन्हें गांवों की स्थिति का पता है? मेरे गांव के दोनों प्राथमिक स्कूल बंद हो गए हैं और चिकित्सा केंद्र का हैंडपंप बारह साल से काम नहीं करता. राजीव को पता नहीं है कि दबाव क्या होता है. हम लाठियों से उनका गला दबा देंगे.

• क्या आपको विपक्षी दलों का सहयोग लेना जरूरी लगता है?

हम कौन-सी पार्टी में जाएं? वे साथ बैठ नहीं सकते. बैठ भी गए तो साथ रह नहीं सकते. क्या सरकार उनकी सुनती है? उनकी बात नहीं चलती.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

चलता है कि शामली तहसील के 300 गांवों में पहले प्रति माह बिजली का भुगतान 15 से 16 लाख रुपए होता था. पिछले अगस्त से नवंबर के बीच यह राशि प्रति माह 40,000 से लेकर 65,000 रुपए तक रही.

टिकैत के गांव सिसौली और पास के भौंरा कलां से एक भी बिल की वसूली नहीं हुई है. बोर्ड के एक अधिकारी ने स्वीकार किया, "बिल न भरने वालों के यहां की लाइन काटना स्थानीय हालात पर निर्भर करता है. हमारे लाइनमैन लाइन काटने के लिए भौंरा कलां गए थे पर गांव वालों ने उन्हें घुसने ही नहीं दिया."

टिकैत ने शायद यह सोचा है कि भुगतान रोकने से सरकार उनकी मांगों पर ध्यान देगी. सरकार टिकैत को गिरफ्तार कर ले यह भी संभव नहीं है, क्योंकि इससे आंदोलन भड़क उठेगा. सरकार ऐसा कदम उठा सकती है, इस अंदेशे से टिकैत ने सिसौली में कहा, "अगर मैं जेल गया तो किसान जो कुछ करेंगे उसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं होऊंगा."

"अगर टिकैत कहेंगे तो हम अपनी फसल भी फूंक देंगे. रेलवे लाइन भी उखाड़ देंगे. दया की भीख मांगने से गोली खाना बेहतर"

सुखबाल सिंह पंवार
आलम गांव, मुजफ्फरनगर जिला.

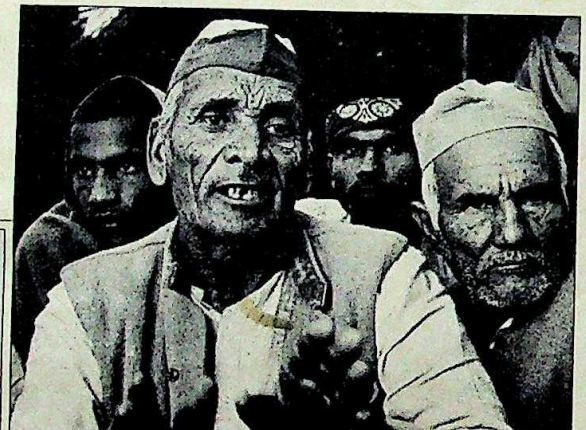

"सरकार ने न तो कभी हमारी सुनी है और न सुनेगी. हमें तो किसी भी तरह मरना ही है"

रामसरूप
दाहा गांव, मेरठ जिला

हरियाणा में जिस तरह देवीलाल ने छोटे किसानों के मुद्दे उठाकर उनको आंदोलित किया था, वही कुछ टिकैत ने यहां भी किया है. किसानों को खेती की पैदावार की उचित कीमत, लागत और कीमत में रिश्ता, किसान के बच्चों की पढ़ाई, और रोजगार की सुविधा बढ़ाने तथा शहर-गांव के बढ़ते फासले को उन्होंने मुद्दा बनाया. ये बातें हर किसान के दिल को छू गईं, चाहे वह जाट हो, राजपूत हो या हरिजन. पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान भी अब टिकैत की जुबान में पूछते हैं कि छुट्टी मनाने और बेटी की शादी पर करोड़ों रुपए खर्च करने वाले मंत्रियों की सरकार यह कैसे कहती है कि उसके पास किसानों की मांगें पूरी करने को पैसा नहीं है. टिकैत यह भी कहते हैं कि पुलिस और सेना की भर्ती में भ्रष्टाचार के कारण किसानों के बेटों को नौकरी नहीं मिलती. इस प्रकार की गड़बड़ियों से वे काफी नाराज हैं और राजीव गांधी को डंडे के जोर से अपनी बात सुनाना चाहते हैं, (देखें भेंटवार्ता).

टिकैत का साधारण किसान होना ही उन्हें भरोसेमंद नेता बनाने का असली कारण है. टिकैत, उनके भाई और इन दोनों के छह बच्चों के पास मुश्किल से 15 एकड़ जमीन है. उनके पास ट्रैक्टर नहीं है और टिकैत एक जोड़ी बैल से अपना खेत जोतते हैं. उनकी मां मुख्तियारी देवी बताती हैं कि टिकैत के बेटों की पढ़ाई का खर्च देने में कितनी मुश्किल होती थी. इन लड़कों ने पढ़ाई तो कर ली पर कहीं नौकरी नहीं मिली और वे खेत में ही काम करते हैं. टिकैत के छोटे से घर की ओर इशारा करते हुए उनके भाई भोपाल सिंह कहते हैं, "अगर 84 गांवों का चौधरी इस हालत में रहता हो तो आप और लोगों की स्थिति का अंदाज लगा सकते हैं."

उनके पूर्वज को चौधरी बनाने पर लोगों ने जो टीका लगाया उसी से इस परिवार के लोगों को टिकैत का उपनाम मिल गया. वे अपनी खाप के प्रमुख हैं. उनके पिता की जब मौत हुई तो वे आठ साल के थे और तभी से प्रमुख बने हुए हैं. आज भी उनका आशीर्वाद पाने वालों की भीड़ लगी रहती है. टिकैत के नायक हैं— सुभाषचंद्र बोस. उनकी बैठक में बोस, गुरु नानक, स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की तस्वीरें लगी हैं. टिकैत ने दान-दहेज के मामले में सामाजिक सुधार भी किया है. और यह इतना फैला कि मेरठ और मुजफ्फरनगर के ग्रामीण इलाकों में चलने वाली बसों में यह नारा लिखा होता है, 'दुल्हन ही दहेज है.'

टिकैत में ऐसा क्या है जो लोग उन्हें नेता मानते हैं? उनकी मां कहती हैं, नेतागीरी की कोई बात नहीं, उसमें सचाई और त्याग की भावना है." इलाके भर के लोग यही मानते हैं. दरअसल हजारों स्वयंसेवकों ने तो जीवनदान पत्र पर दस्तखत करके टिकैत को पकड़ा दिए हैं.ऐसी निष्ठा और अपने गुणों के कारण टिकैत देश की किसान राजनीति में एक लौहपुरुष के रूप में उभरेंगे.

—रामबर सिंह

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उम्मीद पूरी नहीं हुई

लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में 20 फरवरी को राजीव गांधी की आम सभा को बेहद कामयाब बनाने के लिए कांग्रेस और उत्तर प्रदेश के सरकारी अधिकारी पूरे जी-जान से जुटे थे. सड़कों की मरम्मत की गई, बाड़ें लगाई गईं, बड़े लोगों के गुजरने वाले रास्ते को चमका दिया गया. सुरक्षा के लिए होने वाली पूर्व तैयारियों के कारण लखनऊ का ट्रैफिक पूरे हफ्ते अस्तव्यस्त रहा. लेकिन पूरा तामझाम धरा रह गया क्योंकि प्रधानमंत्री हजरत महल पार्क के बगल के स्टेडियम में हेलीकॉप्टर से उतरे. और तो और, पड़ोस के 12 जिलों के लोग बसों की कमी से हफ्ते भर परेशान रहे क्योंकि 3000 बसें किसानों को लखनऊ पहुंचाने के काम में लगा दी गईं.

राजीव की लखनऊ रैली : सरकारी खर्चे पर

हजरत महल पार्क में जो भव्य तैयारी की गई उसे देखकर तो जनता दंग ही रह गई. रैली में शरीक होने वालों को पानी मुहैया कराने के लिए विशेष तौर से पाइप बिछाए गए. राजीव के भाषण को कोने-कोने तक पहुंचाने के लिए क्लोज सर्किट के 200 टीवी सेट लगाए गए. उनके आने से पहले लोगों को जमाए रखने के लिए 'रामायण' सीरियल की झांकियां उन पर प्रसारित की गईं. और आए सिर्फ 2 लाख लोग जबकि मुख्यमंत्री बीरबहादुर सिंह का दावा था कि 15 लाख आएंगे. गैर-सरकारी आंकड़ों के अनुसार पूरे आयोजन पर करोड़ों का खर्च बैठा. एक सरकारी अधिकारी ने कटाक्ष किया, "किसान समर्थक व विपक्ष विरोधी भाषण देने के लिए सभा जुटाने में आखिर खर्च तो होगा ही." और जब मामला महेंद्र सिंह टिकैत और वी.पी. सिंह के असर को काटने का हो तो इतनी कीमत तो कम ही मानी जाएगी कांग्रेसी गणित के हिसाब से.

अफसरों पर आरोप

पटनायक

जानकी बल्लभ पटनायक हालांकि हमेशा दावा करते रहे कि वे खुद ही गरीबी हटाओ कार्यक्रमों की देखरेख कर रहे हैं, पर शायद अब उन्हें लगने लगा है कि कामकाज ठीक से नहीं चल रहा है. इसके लिए उन्होंने अफसरशाही को पूरे तौर पर दोषी बताया है.

दुर्भाग्यवश अफसरों की आलोचना के महीने भर बाद ही पटनायक ने ऐसे कई जिला कलक्टरों का तबादला कर डाला जो पिछड़े इलाकों में गरीबों का भाग्य सुधारने के प्रयास में जुटे थे. ये तबादले इंकाई कार्यकर्ताओं और विधायकों के हस्तक्षेप की वजह से हुए. मसलन संबलपुर के कलक्टर मोहन कुमार धान मिल मालिकों के खिलाफ अपने अलोकप्रिय कदम के कारण सिर्फ साल भर ही उस पद पर रह सके. कोरापुट में पद संभालने के तुरंत बाद ही उन्हें पशु पालन विभाग में भेज दिया गया. इसके अलावा चिन्मय बसु को एक स्थानीय इंकाई नेता का कोपभाजन बनकर सिर्फ आठ महीने में ही गंजम छोड़कर कालाहांडी जाना पड़ा. ये दो उदाहरण भर हैं. ऐसी हालत में अगर अफसरशाही ठीक से काम नहीं कर रही है तो पटनायक को निराश नहीं होना चाहिए.

बसु को नाराज कौन करे

क्या पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु को अपनी व्यक्तिगत आलोचना बरदाश्त नहीं हो पाती? हाल ही में माकपा की राज्य इकाई ने वाममोर्चा सरकार के एक पूर्व वरिष्ठ स्थायी वकील और 1949 से पार्टी के 'कार्ड होल्डर' अरुण प्रकाश चटर्जी की पार्टी सदस्यता का नवीकरण न करने का निर्णय किया. चटर्जी ने मार्च '87 के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. चुनाव हारने के बाद वे राज्य के महाधिवक्ता के पद पर अपनी नियुक्ति की आस लगाए बैठे थे. लेकिन ज्योति बसु ने उनकी जगह अपने नजदीकी नर नारायण गुप्त को इस पद के लिए चुना. चटर्जी ने इसे 'सरासर पक्षपात' बताते हुए माकपा के पोलितब्यूरो के सदस्यों को एक चिट्ठी लिखी. इसके बाद चटर्जी ने खुद को पार्टी से बाहर हुआ पाया. वाममोर्चा के अध्यक्ष सरोज मुखर्जी ने बताया कि चटर्जी के द्वारा बंगला दैनिक 'सतयुग' के संपादक बनने की संतोषजनक व्याख्या न मिलने पर ही यह कदम उठाया गया. लेकिन माकपा के पूर्व सदस्य कहते हैं, "'50 के दशक में मैंने करीब एक दशक तक एक कानूनी पत्रिका का संपादन किया तब मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई." लगता है नेताओं को भी यह अनुचित लगा पर वे बसु को नाराज नहीं करना चाहते.

ज्योति बसु

चटर्जी

इतना आसान नहीं....

किसानों की बढ़ती ताकत का अंदाज लग गया है. पिछले पखवाड़े प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में भारत कृषक समाज के 25वें वार्षिक सम्मेलन में छोटे किसानों के लिए कई रियायतों की घोषणा की और उनकी समस्याओं पर विचार करने के लिए मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाने का आश्वासन दिया. रियायतों में सूखापीड़ित इलाकों में कम समय के कर्जों की वसूली पर रोक लगाना भी शामिल था. जिन जगहों पर लगातार दो वर्षों से सूखा पड़ रहा है वहां कम समय के कर्जों की वसूली की अवधि सात साल कर दी जाएगी और लगातार तीन वर्षों से सूखापीड़ित इलाकों में कर्जे दस साल बाद वापस किए जा सकेंगे. अगर चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन से अधिक हो जाए तो समूचा ब्याज माफ कर दिया जाएगा.

और मजे की बात यह है कि राजीव का भाषण समाप्त होते ही लाल बहादुर स्टेडियम से ज्यादातर श्रोता चले गए. किसानों के राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए थोड़े ही लोग बच गए. यानी इंका का काम आसान होने के आसार नहीं.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गुफा मूर्तियों पर संकट

एलिफेंटा गुफाओं को न सिर्फ प्रकृति से बल्कि मंथर गति से चल रही विनाश की प्रक्रिया से भी खतरा है. पिछले साल 11 सितंबर को गुफा नं. 3 की छत के गिरने के कारणों की जांच में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने पाया कि इस द्वीप से 3 किलोमीटर दूर नावा शेवा पोर्ट ट्रस्ट द्वारा नए जहाजी मालघाट बनाने के लिए समुद्र तल में किए जा रहे विस्फोटों के झटकों से ही गुफाओं

नामस भोजानी

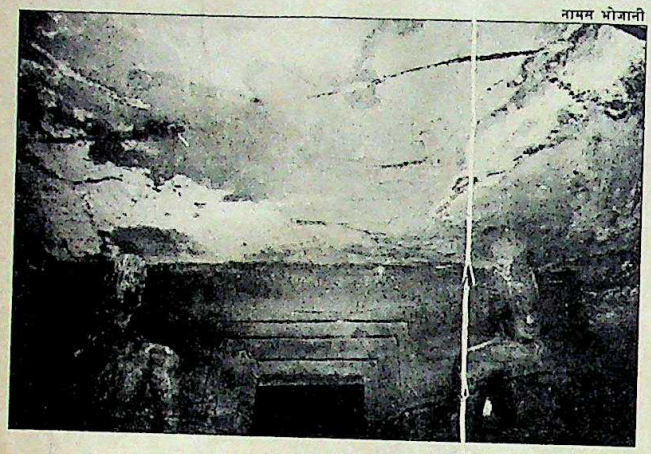

गुफा नं.-1 की छत में दरार : खतरा

को यह खतरा पैदा हो रहा है.

पुरातत्व विभाग ने गुफा नं. 3 में खंभे बनाने का काम शुरू कर दिया है. लेकिन गुफा नं. 1 की छत में दरार के कारण छठी शती में बनाई गई विशाल शिव प्रतिमा को गंभीर खतरा पैदा हो गया है. इस बड़ी गुफा में कई और मूर्तियां हैं. बरसात में छत से पानी रिसने के कारण ये मूर्तियां पूरी तरह भीग जाती हैं. चूंकि गुफा की शिलाएं कमजोर किस्म की हैं इसलिए पानी में भीगने से वे और कमजोर हो जाती हैं और मूर्तियों को नुकसान पहुंचता है.

1957 में इस गुफा की छत पर सीमेंट की 15 सेमी. मोटी परत चढ़ाई गई थी. टूटे-फूटे शिलाखंडों को तराश दिया गया था और दरारों को कंक्रीट से भर दिया गया था. लेकिन सीमेंट की वह परत भी अब छीजने लगी है. गुफाओं की रक्षा के लिए मास्टर प्लान बनाया जाने वाला है. लेकिन मरम्मत में जल्दबाजी नहीं की जाती तो संभव है अगली बरसात और मुश्किल पैदा कर दे.

मजूमदार की मुसीबतें

त्रिपुरा विधानसभा के प्रथम सत्र के शुरू होने के पहले ही मुख्यमंत्री सुधीर रंजन मजूमदार को भावी का आभास होने लगा है. सबसे विवादास्पद मामला तो अलगाववादी गतिविधियों से पीड़ित राज्य में सेना की मौजूदगी का है. 'ट्राइबल नेशनल वालंटियर्स' जैसे गैर-कानूनी संगठन की कारगुजारियों से जूझने के पहले तो मजूमदार को सेना की मौजूदगी की आलोचनाओं से जूझना पड़ेगा. यह कहकर कि हाल का चुनाव इंका सेना की मौजूदगी के बगैर नहीं जीत पाती, माकपा ने यह मुहिम पहले ही छेड़ रखी है. मार्क्सवादियों ने यह आशंका भी जताई है कि राज्य के आदिवासियों पर भी सेना का अत्याचार शुरू हो सकता है. अब यह आरोप भी लग गया है कि उत्तरी त्रिपुरा में आदिवासी स्त्रियों के साथ बलात्कार के तीन मामलों में सेना के जवान शामिल थे. मार्क्सवादी सांसदों बजुबन नारायण कर और अजय विश्वास ने आरोप लगाया है कि उनके पास इससे संबंधित पूरी जानकारी है और वे इसे केंद्र के स्तर पर उठाएंगे.

मजूमदार

वर्चस्व का बखेड़ा

वर्चस्व की अंतहीन लड़ाई में लगता है न तो आइएएस वाले और न ही आइपीएस वाले कोई कसर छोड़ना चाहते हैं. हाल के एक वाकये ने साबित कर दिया कि मध्य प्रदेश भी इस से अछूता नहीं.

पुलिस महानिदेशक एम. नटराजन ने प्रांत के गड़बड़ी वाले इलाकों पर तुरंत पहुंचने के लिए मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब से चार्टर विमान उपलब्ध कराने का प्रस्ताव पिछले साल रखा था. पर इस पर मंजूरी अभी तीन महीने पहले ही मिल पाई है. चूंकि प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से विशाल है और संचार व्यवस्थाएं काफी कमजोर हैं इसलिए यह प्रस्ताव फायदेमंद है. खासकर इसलिए भी कि फ्लाइंग क्लब ने 500 रुपए प्रति घंटे की कम दर पर उड़ान भरने का प्रस्ताव रखा है.

नटराजन

लेकिन वित्त विभाग ने हिसाब लगाकर इस पर कई तरह के सवाल उठाए और पेंच डाल दी कि यह सुविधा प्रधान सचिव और उसके ऊपर के अधिकारियों को ही 'कामचलाऊ' रूप से उपलब्ध हो सकेगी. यानी आइएएस वाले जानते हैं कि अपना रुतबा कैसे कायम रखना है.

विपक्षी भूमिका में मकवाना

गुजरात इंका के कुछ नेता ही विपक्षी की भूमिका निभाने लगे हैं. पिछले पखवाड़े अहमदाबाद में केंद्रीय इस्पात राज्यमंत्री योगेंद्र मकवाना ने अखिल भारतीय केंद्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति कर्मचारी परिषद के सम्मेलन में जो कुछ कहा उससे एक बवाल उठ खड़ा हुआ. उन्होंने कर्मचारियों से कहा कि दूसरे पिछड़े वर्गों के समर्थन पर भरोसा न करें. उन्होंने आरोप लगाया, "गुजरात में जनजातियों और हरिजनों पर ब्राह्मण या दूसरी सवर्ण जातियों के लोग अत्याचार नहीं करते बल्कि अत्याचार पिछड़े वर्गों की तरफ से ही होता है."

लगता है मकवाना अपने भविष्य को सुरक्षित करने के प्रयास में जुटे हैं क्योंकि उनकी राज्यसभा की सदस्यता खत्म होने वाली है. ऐसे बयान वे इस उम्मीद में दे रहे हैं कि हरिजन और आदिवासी पिछड़ी जातियों के नेता, माधव सिंह सोलंकी से नाता तोड़ लेंगे और मुख्यमंत्री अमरसिंह चौधरी के साथ हो जाएंगे. चौधरी का वे समर्थन कर रहे हैं लेकिन हरिजन और आदिवासियों के साथ ही 82 पिछड़ी जातियां इंका के आधार-स्तंभ हैं. इस गणित में उलटफेर हुआ तो इंका को चुनाव में नुकसान उठाना पड़ेगा. उनके इस भाषण की पिछड़ी जातियों के इंकाई नेताओं ने खुलकर भर्त्सना की है. दलितों ने भी इसे 'समाज के विभिन्न वर्गों के बीच दरार डालने के उद्देश्य से प्रेरित' कहकर खेद जाहिर किया. बवाल उठने के बाद मकवाना यह कहकर पीछे हटने लगे हैं कि उक्त शब्द उनके मुंह में ठूंस दिए गए. लेकिन उनके नए बयान पर कुछ ही लोगों को भरोसा है.

मकवाना

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जो प्रमुख टू-व्हीलर निर्माताओं की पसंद है
आप भी वही टायर्स चुनिए

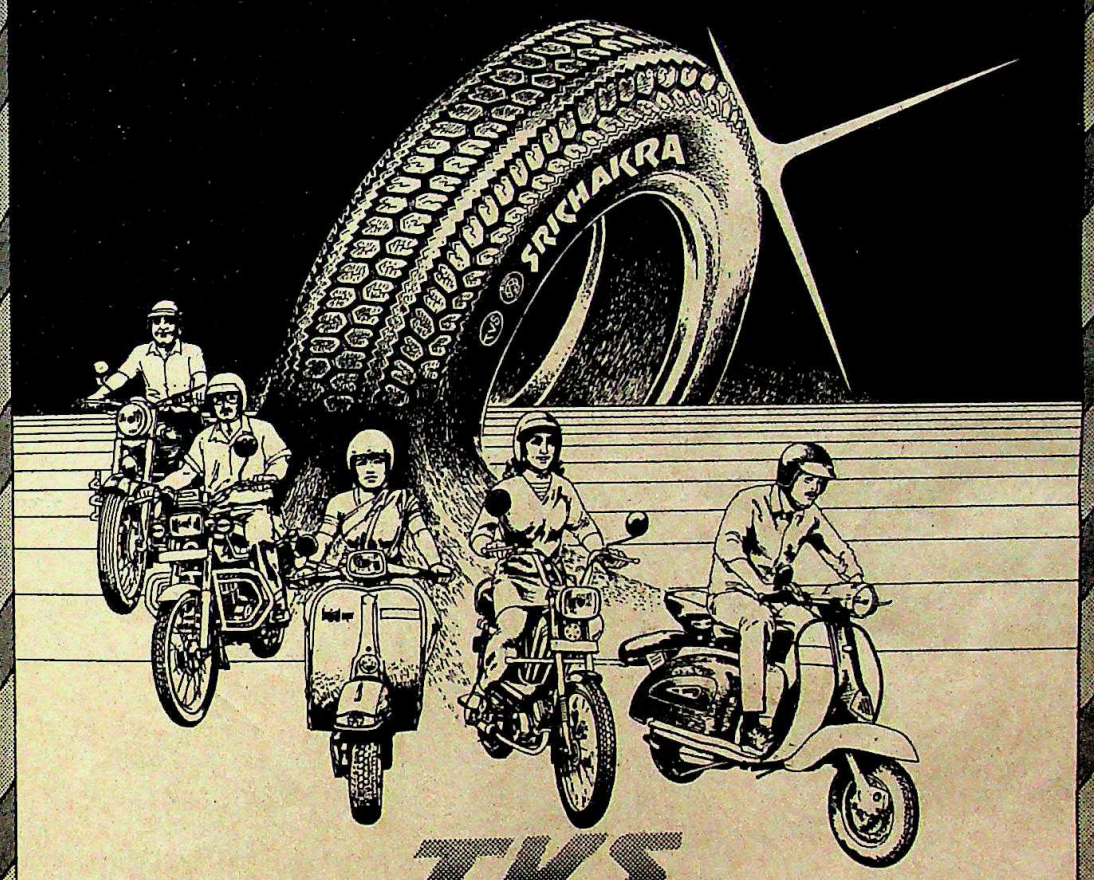

TVS
SRICHAKRA

मौलिक साधन पसंद करने वाले भारत के सभी प्रमुख टू-व्हीलरों के लिए. ज़्यादा सुरक्षा और भरोसेमंद पकड़ के लिए मज़बूत बनाए गए.

सचमुच अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टायर. श्रीचक्रा बनाने वाले हैं टी वी एस - 'ऑटो एन्सीलियरीज़' में जाना-माना एक विश्वसनीय नाम.
भारत के ऊबड़-खाबड़ रास्तों के लिए ख़ासतौर से बनाए गए. श्रीचक्रा टायर ऐसी अनोखी खूबियों से बने हैं जो आपको दें उत्तम कार्यकुशलता और ज़्यादा माइलेज. साथ ही रीट्रेडिंग के लिए इसमें कमाल की गुंजाइश है.
इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सभी प्रमुख टू-व्हीलर निर्माता टी वी एस श्रीचक्रा ही पसंद करते हैं.

STUS453JHN

TVS SRICHAKRA TYRES

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हिंसक बंद से परेशान परिवार दार्जिलिंग छोड़कर जाते हुए

गोरखालैंड आंदोलन

बड़ी बगावत के बगूले

पहाड़ियों में सुलगती आग के ठंडे पड़ने के कोई आसार नहीं

बहत्तर चाय बागानों और दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और कुर्सियांग जैसे पर्यटन स्थलों वाले दार्जिलिंग जिले का नाम भी अब 'अशांत' इलाकों की सूची में जुड़ गया है. क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग पर गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट (जीएनएलएफ) के दो साल पुराने आंदोलन ने इस पूरे पहाड़ी जिले का कामकाज ठप कर दिया है. रिटायर फौजी सुभाष घीसिंग की अगुआई में आंदोलन लगातार विद्रोह में बदलता जा रहा है. भारत कभी नहीं चाहेगा कि उत्तर-पूर्व को शेष भारत से जोड़ने वाले 20 किलोमीटर लंबे 'गलियारे' के आसपास कोई बागी गतिविधि चले. विशेष संवाददाता ***शेखर गुप्ता*** *और मुख्य छायाकार* ***भवान सिंह*** *ने 40 दिन के हिंसक बंद वाले दिनों में उस इलाके का दौरा किया. उनकी रिपोर्ट:*

विशाल हिमालय प्रदेश का एक हिस्सा दार्जिलिंग कभी सिक्किम के राजा के अधीन था. सिक्किम के राजा ने आज से करीब डेढ़ सौ साल पहले इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को नजराने में भेंट कर दिया था. तब के शांत, मनोरम पहाड़ी सैरगाह और आज के इस दार्जिलिंग में जमीन-आसमान का अंतर है. आज यह जैसे एक रणक्षेत्र बन गया है. एक ओर हैं परंपरागत हथियार खुखरी और आधुनिकतम आग्नेयास्त्रों से लैस गोरखा फ्रंट के आंदोलनकारी तो दूसरी ओर बीएसएफ और सीआरपी के 1800 अर्ध-सैनिकों की मदद से तैनात पश्चिम बंगाल की पुलिस. इस रणक्षेत्र में मरने वालों की संख्या पिछले पखवाड़े बढ़कर 30 तक जा पहुंची. लेकिन यह संख्या हालात की गंभीरता बयान करने के लिए काफी नहीं है.

अस्त-व्यस्त जनजीवन और ठप अर्थ-व्यवस्था (देखें बॉक्स) का कहर उठा रहे इस इलाके के लोगों की उम्मीदें दिल्ली पर ही टिकी हैं. वहां गोरखा फ्रंट नेता सुभाष घीसिंग केंद्रीय गृहमंत्री बूटा सिंह और एक रहस्यमय मध्यस्थ के साथ वार्ताओं में जुटे हैं. जैसे-जैसे बातचीत आगे बढ़ रही है, हिंसा भी बढ़ रही है और दार्जिलिंग एक भुतहे शहर में तब्दील होता जा रहा है. इस शहर का उदास सन्नाटा किसी भी शहर के सबसे बुरे दिनों के सन्नाटे से भी भयावह है. तनाव से तने पुलिस वाले अपनी बंदूकों के घोड़ों पर उंगली कसे सड़कों पर गश्त करते रहते हैं. दुकानें तो खुली रखवाने में वे कामयाब हो जाते हैं पर खरीदारों को कैसे ला पाएंगे. उनकी गश्त के कारण सड़कें तो खुली हैं लेकिन सिलीगुड़ी को दार्जिलिंग से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

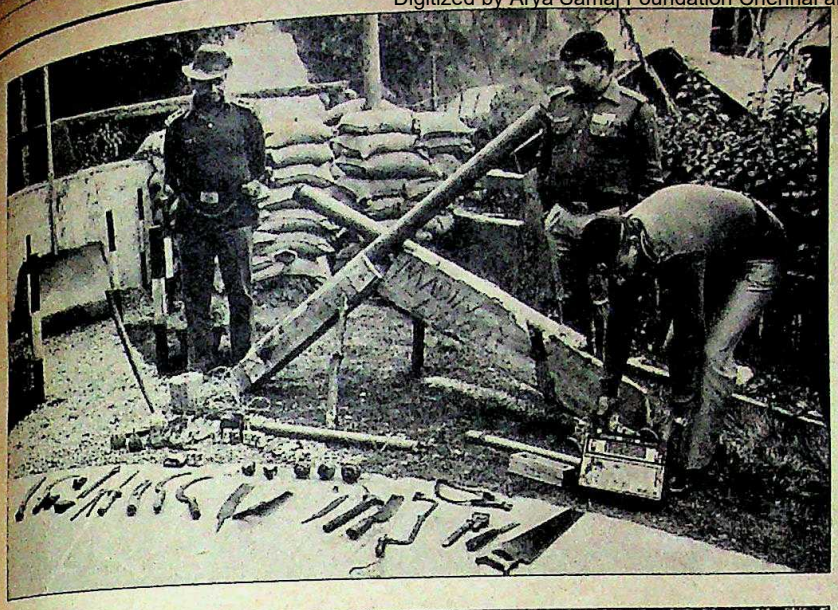

जब्त हथियार; और (नीचे) राजमार्ग को साफ करते जवान: बढ़ती हिंसा

अत्याधुनिक हथियारों की कमी के कारण दार्जिलिंग अभी 'पूर्ण विद्रोह' की चपेट में आने से बचा है. पर ऐसे हथियारों का आना कुछ समय की ही बात है

एक घंटे में बमुश्किल एक वाहन भी नहीं गुजरता जबकि कभी इस पर गाड़ियों का तांता लगा रहता था. आंदोलन ने अपनी हिंसा की छाप इस सड़क पर जगह-जगह छोड़ी है. जगह-जगह बड़े-बड़े पत्थर (जो पहाड़ियों से उन वाहनों पर लुढ़काए गए जिन्होंने आंदोलनकारियों के बंद के आह्वान की उपेक्षा करने की धृष्टता की), जले पेट्रोल टैंकर पड़े थे तो बारूदी सुरंगों के कारण जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे और जला डाले गए लकड़ी के पुल आदि. जिन सड़कों पर पुलिस की चौकसी कुछ कम है वहां हालात और बदतर हैं. दार्जिलिंग से कलिंपोंग और गांतोक जाने वाली मनोरम सड़कों पर कहीं भी एक मील का इलाका ऐसा नहीं बचा है जहां बड़े-बड़े पेड़ काटकर न गिरा दिए गए हों. इनकी शाखाएं जगह-जगह टेलीफोन व बिजली के तारों से उलझी पड़ी हैं, खंभे गिरा दिए गए हैं.

बीएसएफ के सौ जवानों के एक दल के नायक ने कहा, "इससे पहले ऐसी रुकावटें मैंने 1965 की लड़ाई के दौरान कश्मीर इलाके में देखी थीं." ये जवान अपनी मशीनी आरियों और पुराने ढंग की कुल्हाड़ियों से सड़क की सफाई में लगे हैं.

परेशान पुलिस वालों के लिए दार्जिलिंग अब दुश्मन के इलाके की तरह लगने लग गया है. करीब हर रोज सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमले किए जाते हैं. इन हमलों में गोरखा वालंटियर कोर (जीवीसी) के लोग बारूदी सुरंगें, शक्तिशाली हथगोले और स्वचालित हथियार तक इस्तेमाल करते हैं. गोरखा फ्रंट का संस्थापक महासचिव नवीन तमांग पिछले महीने मुठभेड़ में मारा गया. कुर्सियांग के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और कभी स्क्वैश के राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुके रंजीत पचनंदा ने बताया, "वह साहसी था. उसने एक हाथ में पिस्तौल और दूसरे हाथ में स्टेनगन लेकर लगातार गोलियां बरसाईं. उसका हथगोला अगर निशाने पर लगा होता तो हम सबका सफाया हो जाता." तमांग रिटायर सैनिक था. वह पाकिस्तान के खिलाफ 1965 और 1971 की लड़ाइयां लड़ चुका था. कांगो में भेजी गई भारतीय शांति सेना में भी वह था और तब पचनंदा के पिता के अधीन था जो उस समय ब्रिगेडियर थे.

दार्जिलिंग जिले में पड़ने वाली 144 किलोमीटर लंबी भारत-नेपाल सीमा की 11 में से आठ निरीक्षण चौकियां पिछले हफ्ते जला दी गईं. दार्जिलिंग के पास रामम पनबिजली संयंत्र पर दुस्साहसपूर्ण हमला किया गया. और बम फेंककर या जलाकर नष्ट की गईं सरकारी इमारतों की संख्या 250 को पार कर गई.

खुफिया एजेंसियों का अनुमान है कि गोरखा फ्रंट के लड़ाकू दस्ते में तकरीबन 500 प्रशिक्षित लोग हैं. ज्यादातर के पास देसी हथियार ही हैं लेकिन कुछ हथियार तो बहुत ही घातक हैं. पिछले पखवाड़े एक मुठभेड़ के बाद बीएसएफ ने दो तोपें बरामद कीं जो टेलीफोन के खंभों के टुकड़ों और लकड़ी से बनाई गई थीं. इसमें पलीता लगाने की व्यवस्था भी उपयुक्त थी. दूर से विस्फोट की जा सकने वाली बारूदी सुरंगें भी मिली हैं जो वैसी ही हैं जैसी तमिल छापामार श्रीलंका में इस्तेमाल करते रहे हैं. पिछले साल दिसंबर में हिल्लेभंजन में ऐसी ही एक सुरंग के विस्फोट से बीएसएफ का एक ट्रक 40 फीट ऊपर उड़ गया और तीन जवान मारे गए. उग्रवादियों के पास हथियारों के माहिर लोगों की कमी नहीं है. पूरे इलाके में 20,000 तो रिटायर फौजी ही हैं. पकड़े और मारे गए बहुत सारे महत्वपूर्ण उग्रवादी पूर्व सैनिक ही थे. दो तो ऐसे सैनिक भी पकड़े गए जो सेना में काम कर रहे थे और छुट्टियां बिताने आए थे.

अधिकारियों का कहना है कि अत्याधुनिक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हथियारों की कमी के कारण ही यह पूरा इलाका अभी 'पूर्ण विद्रोह' की चपेट में आने से बचा हुआ है. पुलिस के डीआईजी आर.के. हांडा कहते हैं, "लेकिन अत्याधुनिक हथियारों का आना अब सिर्फ कुछ समय की ही बात रह गई है. उग्रवादी अब हताशा में कुछ भी कर सकते हैं." पिछले साल दिसंबर में फ्रंट के लोगों ने घात लगाकर हांडा पर हमला किया था जिसमें वे घायल हो गए थे.

लोगों का रुख उसी तरह का होता जा रहा है जैसा विद्रोह से पहले की हालत में होता है, क्योंकि उग्रवादियों के हर हमले का पुलिस उतनी ही सख्ती से जवाब देती है.

बदले की यह अंधी मानसिकता ही दार्जिलिंग में खून-खच्चर भड़का रही है. जब आंदोलन शुरू हुआ था तो शासक दल माकपा ने इससे गली-मुहल्लों में ही निबट लेने की कोशिश की थी. और जब दोनों ओर से खुखरियां तन गईं तो साफ हो गया कि पलड़ा घीसिंग के लोगों का ही भारी है. दो साल तक सड़कों पर चली लड़ाई में तकरीबन 100 लोग मारे जा चुके हैं.

कलकत्ता में माकपा के महासचिव सरोज मुकर्जी कहते हैं, "देश में सिर्फ यही इलाका है जहां अलगाववादी ताकतों से लड़ाई लड़ी जा रही है. हमारे 62 साथियों ने इसमें अपनी कुरबानी दी है." इस समस्या के लिए

दार्जिलिंग

दम निकल गया

दो वर्षों से चले आ रहे गोरखा आंदोलन ने दार्जिलिंग की अर्थव्यवस्था को तहस-नहस करके रख दिया है. इस इलाके की अर्थव्यवस्था के तीनों प्रमुख आधार—पर्यटन, इमारती लकड़ी और चाय बागान जर्जर हालत में पहुंच चुके हैं.

एक वक्त था जब नवविवाहित जोड़े हनीमून के लिए यहां आते थे. पर अब तो हिम्मती से हिम्मती पर्यटक भी यहां आने का साहस शायद ही जुटा पाए. होटलों का धंधा भी बिलकुल ठप पड़ चुका है. टैक्सी चलाने वालों के भूखों मरने की नौबत आ गई है.

प्रतिदिन हजारों यात्रियों को दार्जिलिंग लाने वाली छोटी रेलगाड़ी एक साल पहले ही बंद हो गई थी. इसकी पटरी का एक बड़ा भाग भूस्खलन की चपेट में आ गया था. आंदोलन चलते रहने से यातायात पटरी पर लाने में और देरी होगी. एक वक्त था जब दार्जिलिंग के सर्वाधिक चहल-पहल वाले इलाके चौरस्ता पर पर्यटकों को माल की सैर कराने के लिए टट्टुओं का जमघट लगा रहता था. अब ये टट्टू इस सूखे पहाड़ी इलाके में चारे की तलाश में दिखाई देते हैं. इंडियन एअरलाइंस के टिकटों की बिक्री बंद के पहले पखवाड़े में पांच हजार रुपए से भी कम की रही. जबकि फरवरी माह में रोज औसतन दस हजार रुपए के टिकटों की बिक्री हो जानी चाहिए.

मार्क्सवादी असर के कारण दार्जिलिंग के चाय बागान हमेशा ही लड़ाकू मजदूर संघों की जन्मभूमि रहे हैं. चूंकि अधिकांश मजदूर नेपाली हैं इसलिए गोरखा फ्रंट ने अब बड़ी सहजता से इन संघों का नेतृत्व मार्क्सवादियों से छीन लिया.

इससे बागान के मैनेजरों के सामने दो प्रतिद्वंद्वी संघों से निबटने की विकट समस्या आ खड़ी हुई है. चाय बागान के एक मैनेजर बताते हैं, "गोरखा फ्रंट आम मजदूर संघों की तरह नहीं. वे तो पक्के फासिस्ट हैं."

दार्जिलिंग चाय उत्पादक संघ के सचिव रानेन दत्ता कहते हैं, "मजदूरों के साथ अब हमारे कोई संबंध नहीं रह गए हैं. पूरा ढांचा ही बिखर चुका है."

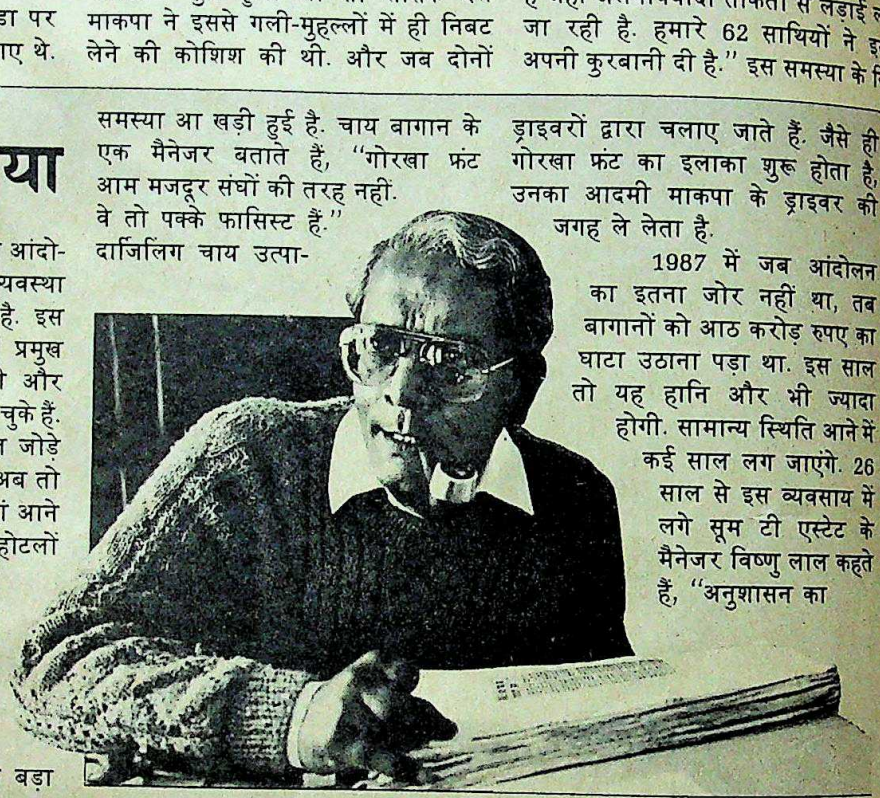

दार्जिलिंग चाय उत्पादक संघ के सचिव रानेन दत्ता कहते हैं, "शांति कायम होने पर जब बागान दोबारा खुलेंगे तो हमारे सामने और समस्याएं होंगी"

दूर-दूर तक फैले चाय बागानों के प्रबंधक अब अपनी एस्टेट को दो विरोधी संगठनों में बंटा देखने के अभ्यस्त हो गए हैं. उदाहरण के लिए सूम एस्टेट का एक भाग माकपा के नियंत्रण में है और बाकी दो गोरखा फ्रंट के नियंत्रण में. नतीजतन चाय बागानों से गुजरने वाले ट्रक दो ड्राइवरों द्वारा चलाए जाते हैं. जैसे ही गोरखा फ्रंट का इलाका शुरू होता है, उनका आदमी माकपा के ड्राइवर की जगह ले लेता है.

1987 में जब आंदोलन का इतना जोर नहीं था, तब बागानों को आठ करोड़ रुपए का घाटा उठाना पड़ा था. इस साल तो यह हानि और भी ज्यादा होगी. सामान्य स्थिति आने में कई साल लग जाएंगे. 26 साल से इस व्यवसाय में लगे सूम टी एस्टेट के मैनेजर विष्णु लाल कहते हैं, "अनुशासन का नामोनिशान मिट गया है."

सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकांश बागान न तो कच्चा माल या ईंधन बाहर से मंगवा सकते हैं, न ही टूटे पुलों और टूटी सड़कों के कारण अपना माल बाहर भेज सकते हैं. पिछले पखवाड़े कम से कम दो दर्जन चाय बागानों का, जिनमें लोपचू और पाशोक जैसे विख्यात बागान भी हैं, शेष दुनिया से संबंध टूट चुका है.

इन हालातों में कुछ चाय कंपनियों के मुनाफे में गिरावट आना अवश्यंभावी है. लेकिन बाकी व्यवसायों की तरह चाय उत्पादकों के सामने कोई और विकल्प नहीं है. अपना बोरिया-बिस्तर समेटकर वे कहीं और तो जा नहीं सकते. एक चाय उत्पादक हताश होकर कहते हैं, "हमने असम में रहकर जीना सीख लिया है और हम असम में ही रहेंगे." गोरखा आंदोलन के बाद यह हताशा दार्जिलिंग के जीवन का जैसे एक अभिन्न अंग बन गई है.

—शेखर गुप्ता

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

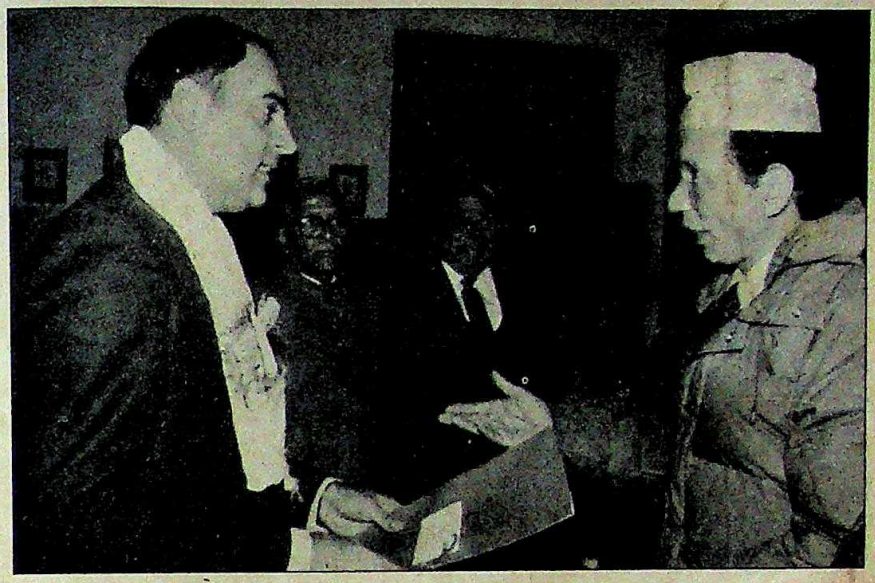

घीसिंग और बसु के साथ राजीव

केंद्र को दोषी ठहराने में वे कोई कोताही नहीं करते, "निश्चित तौर पर केंद्र ने इसे भड़काया और जटिल बनाया है. हालांकि केंद्र सरकार के 200 से ज्यादा दफ्तर जलाए गए हैं, केंद्र और अर्धसैनिक बलों के कई आला अफसरों पर हमले हुए हैं पर नई दिल्ली ने विरोध में कुछ भी नहीं कहा है." हालांकि मुकर्जी मानते हैं कि सरकार कमजोर पड़ रही है, लेकिन वे कहते हैं कि उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ा जाएगा.

लेकिन बदले की यह आग सिर्फ माकपा और गोरखा फ्रंट की रंजिश की वजह से ही नहीं भड़की. अपने विरोधियों का पूरी निर्दयता से सफाया करने के फेर में फ्रंट आतंक का इस्तेमाल करने से कभी बाज नहीं आया. घीसिंग ने तो जिले की दूसरी पार्टियों से यहां तक अपील की थी कि वे उनके साथ आएं या नष्ट होने को तैयार रहें. जिन्होंने इस अपील को नजरअंदाज किया उनका बहिष्कार हुआ. यहां तक कि कलिम्पोंग से गोरखा लीग की विधायिका रेणुलिना सुन्ना को भी नहीं बख्शा गया. अपने नगर में ही उन्हें कई दिनों तक अनाज नहीं मिल पाया. वे अब भी पत्रकारों या संवाददाताओं से बात करने तक में घबराती हैं.

केंद्र गलती ही दोहरा रहा है. वह घीसिंग को भिंडरांवाले की तरह विपक्षी सरकार को परेशान करने में इस्तेमाल कर रहा है

सामाजिक बहिष्कार का तरीका अब ज्यादा क्रूर हो गया है. बहुत से विरोधियों पर हमला हुआ है, उनके घर जला दिए गए हैं. बहुत से अब भूमिगत हो गए हैं, वैसे ही जैसे गोरखा फ्रंट के बहुत से उग्रवादी भूमिगत हैं. छह प्रतिष्ठित नेपालियों ने घीसिंग के खिलाफ बोलने की हिम्मत दिखाई तो उनमें से चार के घर जला दिए गए. कभी जिले की राजनीति पर दबदबा रखने वाले अखिल भारतीय गोरखा लीग के कोषाध्यक्ष संतोष गुरंग कहते हैं, "हम बर्बरता और फासीवाद के साये में जी रहे हैं." प्रांत परिषद के नेता मदन तमांग के मुताबिक, "घीसिंग के साथ मुसीबत यह है कि वे मंद बुद्धि हैं." भारत-नेपाल सीमा पर बने तमांग के घर को गोरखा फ्रंट वालों ने फूंक दिया था. तबाह हो गई संपत्ति में तमांग का पुस्तकालय भी था जिसमें पूर्वी हिमालय पर लिखी गई हजारों दुर्लभ किताबें थीं. तमांग कहते हैं, "कोई भी समझौता हो जाए, मैं यह कैसे भूल जाऊंगा कि मेरा घर जल गया था. मेरी तरह सैंकड़ों लोग हैं जो न माफ कर सकते हैं न भूल सकते हैं." तमांग का तर्क है कि कोई भी समझौता पहाड़ियों की आग को ठंडा नहीं कर सकता है.

उनकी बात में दम भी है. इस बात में संदेह है कि केंद्र से हुआ कोई समझौता शांति बहाल करने में कामयाब हो पाएगा. घीसिंग के लड़ाकू तेवर ने उन्हें नेतृत्वहीन शांत नेपालियों के बीच काफी लोकप्रिय बनाया है. उनके तेवर से एक ऐसे समुदाय को गर्व का भाव मिला है जिसे घरेलू नौकरों और फौजियों की जमात मानकर नकार दिया गया था. जिस लड़ाकू तेवर ने घीसिंग को इतना असरदार आंदोलन दिया है, समझौते के बाद (अगर हुआ तो) वही घीसिंग को भी परेशान कर सकता है.

डर घीसिंग के मन में भी है. अलग राज्य की मांग को खूब हवा मिल चुकी है पर समझौता बहुत तो बहुत दार्जिलिंग को स्वायत्त पहाड़ी जिला परिषद का दर्जा देने पर ही हो सकता है. केंद्र हालांकि उनकी ओर झुका है लेकिन प्रधानमंत्री भाषा के नाम पर एक और राज्य बनाने की मांग स्पष्ट तौर पर नकार चुके हैं. घीसिंग के मौजूदा समर्थकों में ज्यादातर आज यही सोचते हैं कि वे अलग राज्य के लिए ही लड़ रहे हैं, इससे कम किसी चीज के लिए नहीं. तीस्ता बाजार के एक फ्रंट कार्यकर्ता प्रकाश चामलिंग कहते हैं, "वे हमें राज्य का दर्जा कैसे नहीं देंगे, जबकि उन्होंने गोवा को, मिजोरम को, और अरुणाचल को यह दर्जा दे दिया है?" घीसिंग पूरी चालाकी से अपना नुकसान कम करने के फेर में हैं. वे कहते हैं, "जिला परिषद बन जाने के बाद भी मैं राज्य के दर्जे की मांग करता रहूंगा." वे कहते हैं, "मेरे लोग अनुशासित हैं और फ्रंट के फैसले से बंधे हुए हैं. वहां कोई समस्या नहीं होगी."

हालांकि यह एक आशावादी नजरिया लगता है लेकिन नरमपंथी गोरखा भी मानते हैं कि आंदोलन की आतंकवादी आग अब बस से बाहर हो गई है. कमर में खुखरी खोंसे हुए तीस्ता बाजार के पूरन लोहार कहते हैं, "अब समझौता शांति नहीं ला सकता. अगर हम बगावत पर उतर आए तो भारत सरकार पंजाब और श्रीलंका को भूल जाएगी." कलकत्ता में राज्य सरकार के आला अफसर बड़ी उदासी से कहते हैं, "अपने समर्थकों को समझौता मनवाने में नाकाम रहने पर घीसिंग का भी ज्यादा-से-ज्यादा वही हश्र हो सकता है जो संत लोंगोवाल का हुआ था."

पर फिलहाल तो वे भिंडरांवाले की तर्ज पर काम कर रहे हैं. भिंडरांवाले को इंका ने एक महत्वपूर्ण राज्य की विपक्षी सरकार को धमकाने के लिए खड़ा किया था. केंद्र ने घीसिंग को बढ़ावा दिया लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार पर हालात बिगाड़ने का आरोप लगाया. इससे घीसिंग यह समझ बैठे कि केंद्र उनके साथ है. उनके समर्थकों को लगा कि उनका आंदोलन सही है और मांगे जायज. पर लगातार बढ़ रही हिंसा से यही कटु सत्य उजागर होता है कि दार्जिलिंग का आंदोलन उन दोनों पक्षों के काबू से बाहर हो चुका है जो समझौते के लिए प्रयत्नशील हैं.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बूटा सिंह

दरबार के दमनकारी

"बूटा सिंह जी, अब आप अपनी कृपाण अंदर रखिए."

—14 फरवरी 1988 को राष्ट्रपति भवन में गृहमंत्री से राजीव गांधी का मजाक

बात एकदम सटीक थी. लगता है भारी-भरकम शरीर वाले और भड़कीले रंगों की पगड़ियां पहनने वाले इन सिख सज्जन की अचानक हर कहीं तूती बोलने लगी है, मानो राजनैतिक ऑक्टोपस की हर भुजा में कृपाण आ गई हो. एक वार हुआ और तमिलनाडु की अन्नाद्रमुक सरकार औंधे मुंह गिर गई. फिर वार हुआ और मध्य प्रदेश व राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की छुट्टी हो गई. अस्त्र फिर चला और त्रिपुरा की एक दशक पुरानी मार्क्सवादी सरकार का प्रशासकीय फेरबदल के जरिये सफाया कर दिया गया. कृपाण की इसी नोंक पर फारूक अब्दुल्ला दरबार कूच की प्रथा बंद करने का फैसला वापस लेने पर मजबूर हो गए.

कांग्रेसी हलकों के भीतर और बाहर अक्सर चर्चा उठने लगी है कि अपना कोई राजनैतिक आधार न होते हुए भी बूटा सिंह इतने शक्तिशाली कैसे हो गए हैं? प्रोटोकोल के हिसाब से कैबिनेट में उनका नाम मानव संसाधनमंत्री पी.वी. नरसिंहराव और योजनामंत्री पी. शिवशंकर के बाद तीसरे नंबर पर आता है. वे राजनैतिक मामलों, नियुक्तियों और गुप्तचरी संबंधी कैबिनेट समितियों के सदस्य हैं. इंका कार्यसमिति में भी उनकी जगह सुरक्षित है. हाल ही में उनको सौंपी गई नई जिम्मेदारी भी कम आश्चर्यजनक नहीं. उन्हें पेप्सी कोला जैसे विवादास्पद मुद्दे और ऐसे ही दूसरे मामलों पर विचार करने के लिए मंत्रियों की एक टोली का अध्यक्ष बनाया गया. कायदे के मुताबिक तो इस बैठक की अध्यक्षता उद्योग-मंत्री को करनी चाहिए थी. जाहिर है बूटा सिंह राजीव सरकार के सबसे विश्वासपात्र मंत्री बनकर उभरे हैं.

लेकिन उनका यह रुतबा कैबिनेट में उनकी जगह या किसी सरकारी ओहदे की वजह से नहीं है. निस्संदेह इसकी वजह यह है कि संकीर्ण राजनैतिक फायदों की खातिर अपने मंत्रालय की पूरी ताकत जुटाने और फिर उसका प्रयोग

रघु राय

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

करने– या खासकर विपक्षी राज्यों में उसका दुरुपयोग करने– में वे कामयाब रहे हैं भले ही इनमें से कुछ 'फायदें' राष्ट्रीय हितों को कुरबान करके हासिल किए गए पर बूटा सिंह को इसकी कतई चिंता नहीं है. आखिर उनका काम शंकाएं उठाना नहीं बल्कि कर्तव्य निभाना है, क्योंकि वे न तो राजीव के दोस्त हैं और न ही उनके सलाहकार. उनका कोई राजनैतिक आधार या सरकार के भीतर अपनी लॉबी का न होना ही उनकी बेशकीमती राजनैतिक संपत्ति है. न तो उनमें रासपुतिन जैसी सम्मोहक प्रेरक शक्ति है और न ही सीजर जैसी अंधी महत्वाकांक्षा है. सीधे-सादे शब्दों में कहा जाए तो उनकी हस्ती राजीव गांधी के हुक्म पर खांडा चलाने वाले किसी बधिक जैसी है.

वे न तो राजीव के दोस्त हैं और न ही सलाहकार. उनका कोई राजनैतिक आधार नहीं है. यही उनकी राजनैतिक थाती है. वे महत्वाकांक्षी भी नहीं हैं. सीधे-सादे शब्दों में कहा जाए तो वे राजीव गांधी के हुक्म पर खांडा चलाने वाले एक बधिक हैं

जैसा कि बूटा सिंह अपनी भूमिका के बारे में खुद ही बताते हैं, "मुझे लगता है कि लोग मुझे कुछ ज्यादा ही अहमियत दे रहे हैं. मैं सिर्फ वही करता हूं जिसके लिए हमारी पार्टी के नेता मुझसे कहते हैं. और मैं अपनी पूरी क्षमता से उसे पूरा करने की कोशिश करता हूं."

पिछले पखवाड़े ऐसे संकेत मिले कि 'कोई अहमियत नहीं रखने वाला' यह व्यक्ति ज्यादा अहम बनता जा रहा है और गड़-बड़ी वाली इंका सरकारों और विपक्षी राज्य सरकारों पर कुठाराघात करने के लिए उसका प्रयोग और तेजी से किया जाएगा. हालांकि महाराष्ट्र बूटा सिंह की राजनैतिक जिम्मेदारियों की फेहरिस्त में नहीं है, फिर भी प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री चव्हाण को हड़काने का जिम्मा उन्हें ही सौंपा. उन्हें मुख्यमंत्री को साफ-साफ यह बताने के लिए कहा गया कि उनको अपने कुछ मंत्रियों को निकालना होगा और मंत्रि-मंडल में फेरबदल करना होगा. अपने पूर्ववर्ती के साथ बातचीत में बूटा सिंह का स्वर सपाट, निरंकुश और दो टूक था. चव्हाण पहले तो खूब भनभनाए पर जब उन्हें लगा कि वाकई उनका पाला प्रधानमंत्री के खास ऐलची से पड़ा है तो उनका पारा उतर गया. लेकिन इंका के केंद्रीय दफ्तर के सूत्रों का कहना है कि महाराष्ट्र के मामलों में बूटा सिंह ने हाथ सिर्फ इसलिए डाला क्योंकि पहले भी राज्य के मुख्यमंत्रियों के चयन में वे हिस्सा लेते रहे हैं. महाराष्ट्र में इंका विधायक दल के नेता के रूप में अब्दुल रहमान अंतुले और शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर दोनों के चुनावों के वक्त बूटा सिंह को पार्टी पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया था.

मध्य प्रदेश और बिहार के मुख्यमंत्रियों के बिस्तर बंधने के साथ ही इस बात पर रहा-सहा संदेह भी दूर हो गया कि बूटा सिंह प्रधान-मंत्री के हुक्मों की पूरी शिद्दत से तामील कर रहे हैं. दोनों राज्यों में तख्तापलट के काम को उन्होंने न सिर्फ बखूबी अंजाम दिया बल्कि इस बात का भी पुख्ता इंतजाम किया कि यह काम बिना किसी सुगबुगाहट के चुपचाप संपन्न हो जाना चाहिए. मोतीलाल वोरा को बिस्तर बांधने का आदेश प्रधानमंत्री ने या किसी महासचिव ने नहीं बल्कि खुद बूटा सिंह ने ही दिया था.

प्रधानमंत्री के लिए शॉक आब्जर्वर की भूमिका निभाने वाले, बागी राज्य सरकारों को ठिकाने लगाने वाले तथा प्रधानमंत्री को मिलने वाली राजनैतिक चुनौतियां भांपने

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रशांत पंजियार

अपने पद के कारण वे औरों के मुकाबले प्रधानमंत्री तक आसानी से पहुंच पाते हैं. इसीलिए बूटा सिंह की अहमियत बनी हुई है. लेकिन इसी निकटता की वजह से अपने नेता की तरह उन्हें भी लगातार आतंकवादी धमकियों की धौंस में जीना पड़ रहा है

राजीव के साथ (बाएं); और निवास पर सुरक्षा का घेरा

और उनको बेअसर करने के लिए सरकारी मशीनरी या निस्संकोच उपयोग करने वाले इस व्यक्ति की शख्सियत में जी-हुजूरी और चीमड़पन का अद्भुत मिश्रण है. मौलिकता का अभाव ही उनका एकमात्र परिचय है. वे एक धार्मिक व्यक्ति हैं. वे दिन में दो बार गुरबानी का जाप करते हैं और सरकारी बैठकों तथा पत्रकार वार्ताओं तक में हाथ में माला लिए फेरते रहते हैं. वे शायद ही कभी किसी पर बरसते हों. विनम्रता मानो उनके पोर-पोर से झलकती है. उनके हाथ अक्सर नमस्ते की मुद्रा में उठते हैं और किसी से मिलते ही कह उठते हैं, "तुस्सीं ता साड्डे मेहरबान हो."

गृहमंत्री के रूप में वे सिर्फ अपने अधिकारियों के मार्फत ही कामकाज करते हैं. यहां तक कि साप्ताहिक समीक्षा के लिए होने वाली बैठकों में, जिसमें उनके दो कनिष्ठ मंत्री और बड़े अफसर शामिल होते हैं, संवेदनशील विषयों पर भी वे औरों को ही बोलने देते हैं. लेकिन राजनैतिक विषयों पर वे हमेशा अपना निचोड़ पेश करते हैं. अफसरों की नियुक्ति और अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती जैसे मामलों में चिदंबरम को खुली छूट दे दी गई है. और राजनैतिक कारणों से नितांत जरूरी न हो ऐसी अंतरराष्ट्रीय समस्याओं का निबटारा मृदुभाषी चिंतामणि पाणिग्रही ही करते हैं. गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "गृह मंत्रालय की टीम में बूटा सिंह के रूप में एक बुलडोजर, चिदंबरम के रूप में एक मेधावी पर विनम्र व्यक्ति और चिंतामणि के रूप में एक चुपचाप काम करने वाले व्यक्ति का समावेश है. लेकिन बूटा सिंह को हमेशा सिर्फ अपने नेता की ही चिंता लगी रहती है."

जालंधर से 15 किमी दूर मुस्तफापुर गांव में पले-बढ़े बूटा सिंह में सात साल की उम्र से ही सफाया करने की प्रवृत्ति दिखने लगी थी. उनकी बड़ी बहन 57 वर्षीया प्रीतम कौर याद करती हैं कि उनके एक चाचा ने एक बार बूटा सिंह को मधुमक्खियों का छत्ता दिखाकर कहा कि यह छत्ता मधु से लबालब भरा है. दो दिन बाद परिवार के सदस्यों ने एक चीत्कार सुनी. वे खेत की तरफ भागकर गए तो देखा बूटा सिंह मक्खियों के दंश से जमीन पर पड़े कराह रहे थे.

बूटा सिंह के हरिजन परिवार के लिए वे दिन भयंकर गरीबी के थे. उनके पिता गांव-गांव में घूमकर हाथ से बुने कपड़े बेचकर परिवार का भरण-पोषण करते थे. लेकिन उस वक्त भी बूटा सिंह में कभी हार न मानने की जिद थी. वे अपने पिता के पेशे को अपनाने नहीं जा रहे थे. खींचतान कर उन्होंने आखिरकार जालंधर के खालसा कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ही ली. कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने साम्यवादी साहित्य पढ़ना शुरू कर दिया था और साम्यवादी मुखपत्र 'द फुलवारी मैगजीन' में प्रूफ रीडर की नौकरी कर ली थी. रूस में हुई क्रांति से वे इतने प्रभावित थे कि प्रेस में काम खत्म करने के बाद अक्सर बिजली के खंभे के नीचे बैठकर साम्यवादी साहित्य पढ़ते रहते. 1953 में जब स्तालिन का देहांत हुआ तब बूटा सिंह खूब रोए थे. अब वामपंथी पंजाबी दैनिक 'नवां जमाना' में काम कर रहे उनके प्रूफ रीडर साथी कुलबीर सिंह ने याद कर बताया, "स्तालिन की मौत के बाद तीन दिनों तक वे इतने उदास रहे मानो उनके परिवार का ही कोई मर गया हो."

इसके बाद इस नौजवान मार्क्सवादी ने अपना गांव छोड़ा और इतिहास में एम.ए. करने के लिए बंबई के गुरु नानक खालसा कॉलेज में चले गए. पढ़ाई खत्म कर जब वे जालंधर लौटे तब वे अकेले पढ़े-लिखे हरिजन थे. इसके बाद साम्यवादी चोला उतारकर उन्होंने 'अकाली पत्रिका' में उप-संपादक की

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रघु राय

मौका मिले उसी में शामिल होना चाहिए. उस समय सभी राज्यों में कांग्रेस का राज था. इसलिए जब पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गुरमुख सिंह ने उनसे कांग्रेस में शामिल होने को कहा तब वे प्रस्ताव स्वीकार करने में जरा भी न झिझके. और उसके बाद से तो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं. जब कांग्रेस में टूट हुई तब उन्होंने इंदिरा गांधी का पक्ष लिया. जनता राज में भी कांग्रेस महासचिव के रूप में वे उनके साथ मजबूती से डटे रहे.

यह विडंबना ही है कि स्तालिन की मौत पर आंसू बहाने वाले व्यक्ति को ही त्रिपुरा की मार्क्सवादी सरकार को उखाड़ फेंकने की जोड़-तोड़ करने के लिए चुना गया. इस प्रक्रिया में उन पर धोखाधड़ी और फरेब के कई आरोप लगे सो अलग. लेकिन कुछ भी हो, इस काम से राजीव गांधी का मुख्य सिपहसलार होने की उनकी छवि मजबूत ही हुई है. तत्कालीन मुख्यमंत्री नृपेन चक्रवर्ती ने मतदान से पूर्व हिंसा पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र से सहायता की मांग की थी. चक्रवर्ती से त्रिपुरा में सुरक्षा बलों की तैनाती का अनोखा करार करने के लिए बूटा सिंह 25 जनवरी को विमान से अगरतला पहुंच गए. एक बार जब राज्य सरकार लिखित रूप में बाध्य हो गई तब उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों के बजाय पूरे राज्य को ही अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया और मतदान के 48 घंटे पहले राज्य को सेना के हवाले कर दिया. विपक्ष ने आरोप लगाया कि सेना की संगीनों के साये में निष्पक्ष मतदान नहीं हुआ और मतदाताओं को इंका को वोट देने के लिए डराया गया था.

शायद त्रिपुरा आज भी इसका सटीक उदाहरण है कि गृहमंत्री गृह मंत्रालय की शक्ति और संसाधनों का प्रयोग कैसे क्षुद्र राजनैतिक फायदों के लिए कर रहे हैं और सरकार के इस सबसे शक्तिशाली हथियार के इस्तेमाल से सत्ताधारी पार्टी और सरकार के बीच का फर्क किस तरह मिट गया है. हालांकि बूटा सिंह के गृहमंत्री बनने से पहले ही राजीव गांधी की सरकार ने यह रवैया अख्तियार कर लिया था लेकिन अब तो इसे स्थापित नीति के रूप में ही स्वीकार कर लिया गया है.

नौकरी कर ली. उसी समय वरिष्ठ अकाली नेताओं की उन पर नजर पड़ी. उनमें से एक हलबीर सिंह कहलों ने बूटा सिंह की पढ़े-लिखे पिछड़े युवक की छवि का लाभ लेना चाहा और पार्टी के काम के लिए उन्हें नियुक्त कर लिया. 1962 में तीसरे लोकसभा चुनाव में रोपड़ सुरक्षित क्षेत्र से शिरोमणि अकाली दल ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया. लेकिन तीन साल बाद अकालियों में जाति-गत आधार पर फूट पड़ गई और संत फतेह सिंह और मास्टर तारा सिंह के दो अलग-अलग गुट बन गए. बूटा सिंह तारा सिंह गुट में शामिल हो गए.

तंगी और कठिनाई के दिनों ने बूटा सिंह को सिखा दिया था कि जो भी सामाजिक और आर्थिक फायदे मिलें उन्हें लेते रहना चाहिए. इसलिए जिस किसी संगठन में तरक्की का

बूटा सिंह और बरनाला (एकदम दाएं): उठापटक के बावजूद घनिष्ठता

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सुभाष घीसिंग और गोरखालैंड आंदोलन से निबटने में भी गृह मंत्रालय यह रवैया बहुत ही खौफनाक तरीके से अपना रहा है. मार्क्सवादियों का आरोप है कि केंद्र के पिछले साल के क्रियाकलापों से यह साफ हो गया है कि ज्योति बसु की वामपंथी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बूटा सिंह सुभाष घीसिंग को भिंडरांवाले के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन यह आंदोलन भी अब हाथ से निकलता जा रहा है. अगर गृह मंत्रालय की मशीनरी के दुरुपयोग से त्रिपुरा में लोकतंत्र की हत्या की गई तो केंद्र की कारगुजारियों के कारण पश्चिम बंगाल के एक खूबसूरत जिले दार्जिलिंग को अराजकता की आंधी में झोंक दिया गया है. लेकिन बूटा सिंह इन आरोपों का खंडन करते हैं. वे स्वीकार करते हैं, "ज्योति बसु की पूर्व अनुमति और अनुमोदन के बगैर किसी भी स्तर पर हम घीसिंग से नहीं मिले. प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकार की पीठ पीछे कुछ भी नहीं होगा."

मंत्रालय का उपयोग पार्टी के काम के लिए करने का मामला तमिलनाडु में साफ दिखा. जब प्रधानमंत्री मेघालय में चुनाव प्रचार करने गए थे तो उन्होंने बूटा सिंह से कहा था कि वे जानकी गुट द्वारा विधायकों की खरीद-फरोख्त वाले आरोप की जांच करें. गुप्तचर विभाग के अधिकारियों ने इस राजनैतिक मसले पर जासूसी करने के लिए मद्रास के एक पांच सितारा होटल में डेरा डाला. बूटा सिंह ने वहां से मिली सूचनाएं 48 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री तक भेजीं और राज्यपाल सुंदरलाल खुराना को जानकी सरकार को बरखास्त करने का संकेत दिया. लेकिन इस प्रक्रिया में बूटा सिंह को फिल्म अभिनेता शिवाजी गणेशन जैसे इंका नेताओं के आरोप सहने पड़े. गणेशन ने बूटा सिंह पर दोमुंहेपन का आरोप लगाया.

जब गैर-इंका शासित राज्यों के नए राज्यपालों की नियुक्ति का मामला आया तो बूटा सिंह ने सरकारिया आयोग की सिफारिशों को ताक पर रखते हुए इस बात का पक्का बंदोबस्त किया कि पुराने भरोसे के नौकरशाह और इंका के लोग ही राज्यपाल बनें ताकि वे मुख्यमंत्रियों के कामकाज पर नजर रख सकें. हालांकि गृहमंत्री कहते हैं कि इन नियुक्तियों से पहले उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों से सलाह मशविरा किया था पर हरियाणा के मुख्यमंत्री देवीलाल उनके दावे का खंडन करते हैं. बल्कि देवीलाल तो हरिआनंद बराड़ी, जो गुप्तचर ब्यूरो के प्रमुख रह चुके हैं, का नाम हरियाणा के राज्यपाल के रूप में देखकर दंग रह गए. लेकिन बूटा सिंह कहते रहे, "बराड़ी की नियुक्ति के मामले में मैंने खुद देवीलाल से बात की थी और उन्होंने 'हां' की थी."

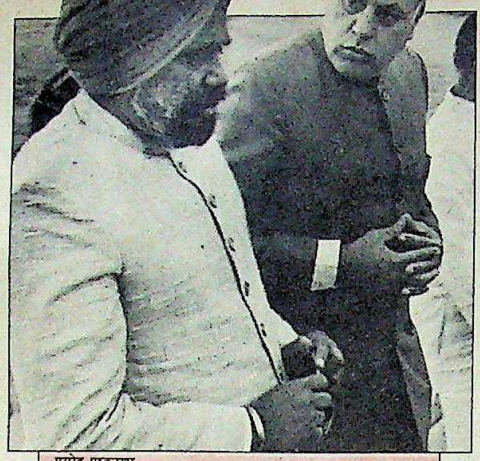

प्रमोद पुष्करणा

पाना

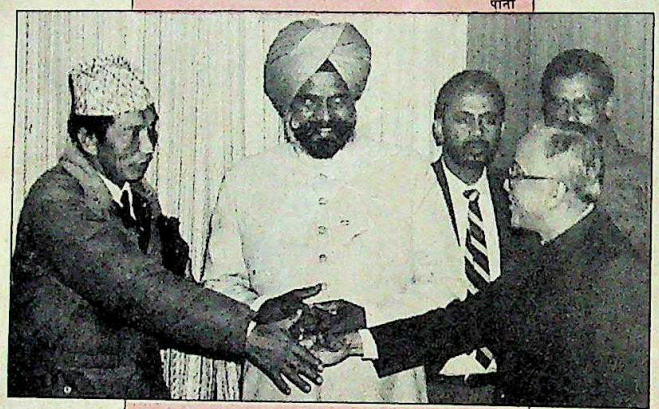

पाना

बूटा सिंह के गृहमंत्री रहते केंद्र-राज्य संबंध, आतंकवाद, पंजाब, सांप्रदायिकता यानी हर समस्या बिगड़ती ही गई है. उनकी असफलता दरअसल दिल्ली दरबार की असफलता ही है

गृहमंत्री के पद का इस्तेमाल पार्टी के काम के लिए करने में तो वे कामयाब रहे लेकिन सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर वे अपने लोगों को नहीं बैठा पाए. जैल सिंह और चव्हाण जैसे उनके पूर्ववर्ती गृहमंत्रियों ने बैंकों के अध्यक्ष, लोकसेवा आयोग के सदस्य और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के अध्यक्ष पद पर अपने लोग भर लिए थे लेकिन इस मामले में बूटा सिंह का रिकार्ड बहुत ही कमजोर है.

श्रीमती गांधी के राजनैतिक जीवन के सबसे बड़े संकट, ऑपरेशन ब्लू-स्टार के समय बूटा सिंह उनके लिए संकट-मोचक साबित हुए. उन्होंने लंदन की अपनी यात्रा अधूरी छोड़ दी और अकाल तखत की कार सेवा आयोजित करने के काम में जुट गए. जब कोई ग्रंथी कार सेवा के लिए राजी नहीं हुआ तो बूटा सिंह पटना के एक ग्रंथी को इस काम के लिए राजी करके ले आए. तब वे निर्माण-मंत्री थे और इस नाते अकाल तखत के पुनर्निर्माण में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अनुभव का उन्होंने खूब इस्तेमाल किया.

संयोगवश वे हर अहम मौके पर 'सेवा' के लिए उपलब्ध रहे हैं. एशियाड के समय वे खेलमंत्री थे और ऑपरेशन ब्लू-स्टार के समय निर्माणमंत्री. जब राजीव गांधी की अपने ममेरे भाई अरुण नेहरू से अनबन रहने लगी तो खाली जगह भरने के लिए गृहमंत्री की कुर्सी पर आ गए. नेता के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने के क्रम में उन्होंने

(ऊपर से) बूटा सिंह और फारूक; उनके अगल-बगल घीसिंग और ज्योति बसु; तथा रिबेरो के साथः हर कहीं मौजूद

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रमोद पुष्करना

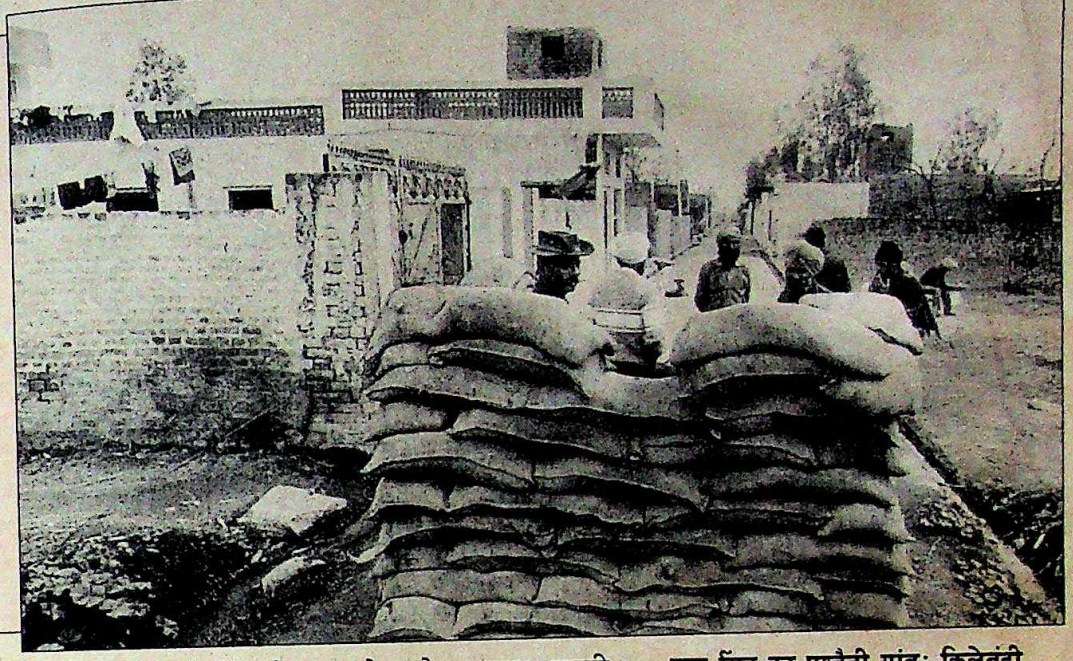

उनके परिवार के सात लोगों की हत्या के बाद उनके रिश्तेदारों के गांव मुस्तफापुर और जल्लोवाल स्थित घरों पर आजकल सीमा सुरक्षा बल की एक-एक प्लाटून पहरा देती है

बूटा सिंह का पुश्तैनी गांवः किलेबंदी

मंत्रिमंडल के अपने वरिष्ठ साथी विश्वनाथ प्रताप सिंह के खिलाफ जहर उगलने में भी हिचक नहीं दिखाई. जब फेयरफैक्स मामले में मंत्रिमंडल की बैठक हो रही थी तो उन्होंने वी.पी. सिंह पर पीठ में छुरा घोंपने का इलजाम लगाया. बाद में लोकसभा में वी.पी. सिंह जब फेयरफैक्स विवाद पर अपनी सफाई देने खड़े हुए तो बूटा सिंह ने उन्हें रोकने की कोशिश की. ऐसा पहली बार हुआ कि जब एक मंत्री ने अपने ही साथी को संसद में बोलने से रोकने की कोशिश की. कहा जाता है कि उन्होंने ही गृह मंत्रालय में अरुण नेहरू के 'कारनामों' के रोमांचक किस्से अपने करीबी पत्रकारों को सुनाए थे. यह उन्हीं के कहने का प्रताप था कि आंतरिक सुरक्षा विभाग द्वारा चेकोस्लोवाकिया से पिस्तौलों की खरीद के मामले में जांच के आदेश दिए गए. विपक्षी दलों के शासन वाले राज्यों में जब वे गए तो उन्होंने गैरजिम्मेदार होने की हद तक विषवमन किया. जैसे आंध्र के एक दौरे में उन्होंने रामराव सरकार को राष्ट्र विरोधी कह दिया.

पिछले हफ्ते जब आतंकवादियों ने 36 घंटे के अंदर 30 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी तो उन्होंने राज्यपाल सिद्धार्थ शंकर राय और पुलिस प्रमुख रिबेरो को फोन करके डांट लगाई. उन्होंने उनसे सख्त लहजे में अपनी नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करने को कहा. 1980 के बाद से वे पहले गृहमंत्री हैं जिन्हें पड़वही वाले राज्यों के कानून और व्यवस्था की पूरी-पूरी जिम्मेदारी मिली हुई है. लेकिन जानकार लोग यह देखकर हैरान हैं कि ऐसे राज्यों के मामलों में उनकी लगातार नाकामियों और घालमेल के बावजूद उनकी बेसाख्ता चल रही है. लेकिन इस बारे में बूटा सिंह का नजरिया साफ है. वे कहते हैं, "पंजाब में अलगाववाद के बीज 1978 में अकाली दल द्वारा आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पास करने के साथ ही पड़ गए थे. उसके बाद से तो अकाली दल के अनेक धड़े सिर्फ इसी बात को साबित करने के लिए लड़ रहे हैं कि सिर्फ वे ही सिखों के हितों के रक्षक हैं. वे प्रचार करते रहे हैं कि सिखों के साथ भेदभाव किया जा रहा है. बूटा सिंह का पक्का मानना है कि सभी सांप्रदायिक ताकतों को सख्ती से कुचलना होगा. वे कहते हैं, "हर आदमी को अपना धर्म मानने, उसका प्रचार करने की आजादी होनी चाहिए पर उसे किसी पर अपना मत थोपने की आजादी नहीं दी जा सकती. जो लोग धार्मिक स्थलों का उपयोग राजनैतिक स्वार्थों और दूसरों के खिलाफ घृणा फैलाने के लिए करते हैं हमें उन लोगों को कुचलना ही होगा."

लेकिन इसी तरह के राजनैतिक जवाब सत्तारूढ़ दल के नेता अक्सर देते रहते हैं. बूटा सिंह का मानना है कि जब तक आतंकवादी हिंसा नहीं छोड़ते तब तक बातचीत से समस्या का समाधान संभव नहीं है. वे कहते हैं, "हम बातचीत से मसले को सुलझाने के खिलाफ नहीं हैं. लेकिन बंदूक के जोर पर बातचीत नहीं हो सकती. उधर से कोई ऐसा एक नेता तो आए जो यह दावा कर सके कि वह हिंसा बंद करा सकता है और यह दावा करे कि वे लोग देश की अखंडता में आस्था रखते हैं." लेकिन बूटा सिंह गुपचुप तौर पर पंजाब समस्या के राजनैतिक समाधान की कोशिश भी करते रहे हैं. हाल के महीनों में वे मंत्रिमंडल की बैठकों में कहते रहे कि कोई सर्वमान्य नरमपंथी सिख नेतृत्व ही शांति कायम करा सकता है. और इसी उद्देश्य के लिए अकाली नेताओं से पोशीदा तौर पर बात चलाई गई और बाद में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को जेल से छोड़ा गया. केंद्र को उम्मीद थी कि बादल अकाली दल के धड़ों और उग्रवादियों को एकजुट करने में कामयाब होंगे. लेकिन नतीजा ठीक उलट निकला. उग्रवादियों के हाथ की कठपुतली बन गए बादल वह भूमिका निभाने में असमर्थ रहे हैं जिसकी उम्मीद केंद्र ने उनसे की थी.

बूटा सिंह को गांधी दरबार के प्रति स्वामीभक्ति दिखाने की पंजाब और दूसरी जगह भारी कीमत चुकानी पड़ी है. ज्यादातर सिख उन्हें दिल्ली दरबार का दास और 1984 में सिखों पर जुल्म ढाने के लिए जिम्मेदार मानते हैं और उनका नाम आते ही नाक-भौं सिकोड़ने लगते हैं. अकाल तखत की कार सेवा कराने में उनकी भूमिका के लिए उन्हें तनखैया करार दिया गया और आज तक वे समाज से बहिष्कृत ही हैं. सितंबर 1984 में जब उनकी मां मरीं तो दिल्ली का कोई भी ग्रंथी उनका अंतिम संस्कार कराने को तैयार नहीं हुआ. इसके लिए तखत हरमिंदर साहिब, पटना के ग्रंथी बुलाए गए.

जिस राज्य में बूटा सिंह पैदा हुए वहां उनका कोई राजनैतिक आधार नहीं है.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

एक बार जैल सिंह ने बड़ी अपमानजनक भाषा में उनसे कहा कि प्रधानमंत्री उनके साथ घरेलू नौकर से भी बदतर व्यवहार करते हैं तो गृहमंत्री ने जवाब दिया कि वे इसी से संतुष्ट हैं

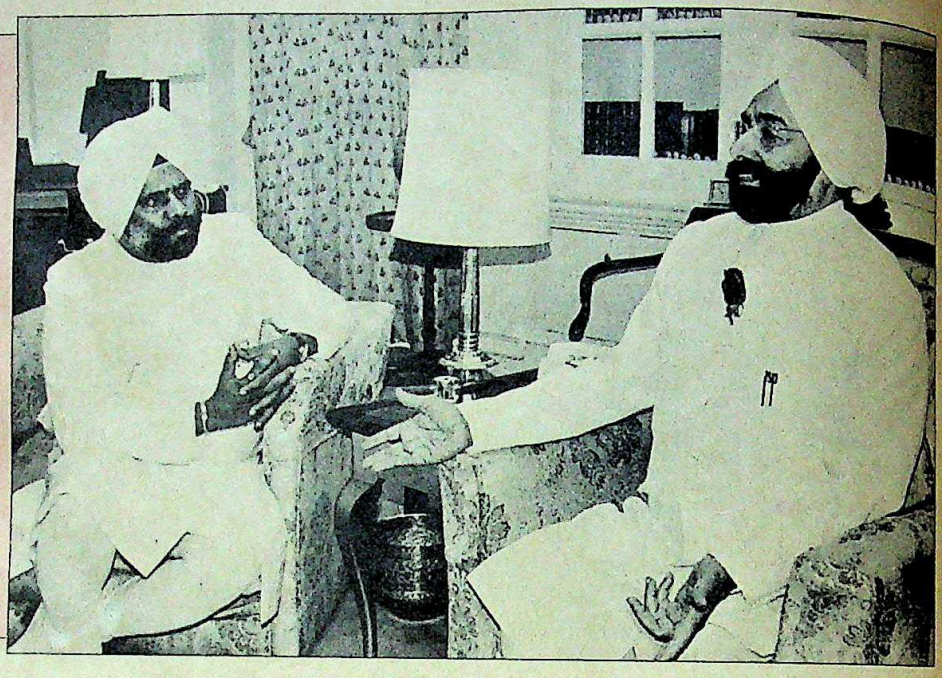

सिखों का सम्मान पाने के लिए बूटा सिंह उन प्रमुख गुरद्वारों में गए जो इंका शासित राज्यों में हैं. उन्हें पटना तथा नांदेड़ में सरोपा भेंट किए गए. दर्शन सिंह रागी को भी ऐसा करने के संदेश भेजे गए पर स्वर्ण मंदिर के कामकाज पर उनका कम ही वश चलता था इसलिए ऐसा नहीं हो पाया.

शिरोमणि गुरद्वारा प्रबंधक समिति में अपना असर बढ़ाने के लिए उन्होंने 1986 में हुए समिति के चुनावों में परदे के पीछे से सक्रिय भूमिका निभाई. लेकिन उनकी कोशिश का नतीजा उलटा ही हुआ और अधिकांश उदारपंथी अकाली उग्रवादियों और तोहड़ा के लोगों के हाथों हार गए.

अपने नेता राजीव गांधी की तरह बूटा सिंह को भी लगातार आतंकवादियों की धमकियां मिलती रही हैं. उनके दोनों बेटे भी सशस्त्र पुलिस के पहरे में ही कहीं आते-जाते हैं. अपने परिवार के खात्मे की आतंकवादियों की योजना संबंधी गुप्तचर रिपोर्टों से लगता है कि उनके मन में भी डर बैठ गया है. उनके गांव में परिवार के सात लोगों की हत्या के बाद यह डर और बढ़ा है. उनके रिश्तेदारों के मुस्तफापुर और जल्लो-वाल गांवों में अब सीमा सुरक्षा बल की एक-एक प्लाटून पहरा देती है. बूटा सिंह लॉन में धूप सेंकने के लिए भी बैठते हैं तो कारबाइन से लैस कमांडो बंगले के झाड़ी-दार घेरे के अंदर गश्त कर रहे होते हैं. और यह डर इस हद तक जा पहुंचा है कि जब एक सिख सांसद ने सुरक्षा गार्ड रखने से इनकार कर दिया तो बूटा सिंह को लगा कि इस सांसद की आतंकवादियों से छनती है.

सुरक्षा कारण हो या कुछ और, बूटा सिंह से मिल पाना काफी मुश्किल है. उनके घर पर काम करने वाले उनके सहायक बाहर वालों से खिड़की से ही बात करते हैं. उनके राजनैतिक सहायक को ढूंढ़ पाना भी काफी मुश्किल है. और मिलने का समय देकर उसे रद्द करने के बारे में वे कुख्यात हैं. बूटा सिंह का एक और गुण, जो राजीव गांधी को राजनैतिक रूप से माफिक आता है, वह है अपमान सह लेना और जरूरत पड़ने पर किसी के सामने सिर झुका देना. जब पूर्व राष्ट्रपति जैल सिंह और प्रधानमंत्री के बीच तनाव बहुत बढ़ गया तो बूटा सिंह ने इस फासले को कम करने की कोशिश की.

और रूठे को मनाने की अपनी गजब की क्षमता दिखाते हुए उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति को 'युद्ध विराम' के लिए राजी कर ही लिया. एक बार जैल सिंह ने बड़ी अपमानजनक भाषा में जब उनसे कहा कि प्रधानमंत्री तो उनके (बूटा सिंह के) साथ घरेलू नौकर से भी बदतर व्यवहार करते हैं तो गृहमंत्री ने पलटकर जवाब दिया कि वे इस व्यवहार से ही संतुष्ट हैं.

प्रधानमंत्री की गुलामी में भी जिस आदमी को आनंद आता हो उसके गृहमंत्री रहते हुए इस मंत्रालय का स्वतंत्र ढंग से काम करना संभव नहीं है. उनके अधीन कुछ महीनों तक गृह राज्यमंत्री रहने वाले अरुण नेहरू कहते हैं, "ऊपर से 'हां' हुए बिना हिल भी नहीं सकने वाले आदमी का इतने महत्वपूर्ण मंत्रालय में रहना देश के लिए खतरनाक है. रोज-ब-रोज लिए जाने वाले फैसलों के लिए तो तेजतर्रार और स्वतंत्र-चेता व्यक्ति चाहिए." गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं, "बूटा सिंह की असली संपत्ति तो नेहरू-गांधी परिवार के प्रति उनका पूर्ण समर्पण ही है. वे तो प्रधानमंत्री के चपरासी का 'आदेश' भी मान सकते हैं." बूटा सिंह भी मानते हैं, "मैं इस पद पर सिर्फ गांधी परिवार के चलते ही हूं. एक गरीब आदमी को इतने नीचे से उठाकर गृहमंत्री की कुर्सी पर बैठा देने के लिए मैं जीवन भर उनका आभारी रहूंगा."

बूटा सिंह के गृहमंत्री रहने के दौरान केंद्र-राज्य संबंध, आतंकवाद, पंजाब, सांप्रदायिकता, कानून और व्यवस्था, सीमा पर तनाव सभी समस्याएं बिगड़ती ही गई हैं. लगता है कि हरेक समाधान के एवज में वे एक नई समस्या खड़ी कर लेते हैं. उनके आलोचक भी मानते हैं कि वे दरबारी हैं और उनकी असफलता दिल्ली दरबार की असफलता है.

राजीव और बूटा सिंह का रिश्ता सह-जीवी का है. अच्छी टीम न बना पाने के कारण राजीव उनकी राय सबसे ज्यादा मानते हैं. राजीव को बूटा सिंह की उतनी ही जरूरत है जितनी बूटा सिंह को राजीव की. पर जैसा कि राजीव के करीबी एक बड़े अफसर कहते हैं, अहम सवाल यह है कि राज्यरूपी जहाज ऐसे कमजोर और ढीले-ढाले नेतृत्व के हाथों कब तक सुरक्षित रह सकेगा.

—प्रभु चावला और पंकज पचौरी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पांच बातें कभी न भूलें

ये आपके लिये सदैव लाभकारी रहेंगी.

1

अपनी बैंक पास-बुक अन्तिम तिथि तक दुरुस्त रखें। इससे आपके पास अपने आय-व्यय का पूरा विवरण रहेगा और उलझन की स्थिति से भी बचेंगे।

2

ध्यान रखें कि आपको अपने चालू खाते का पूर्ण-विवरण यथासमय प्राप्त होता है – बिना मांग किये।

3

आपकी चैक बुक और पास बुक सुरक्षित रखी गयी है इसका पूरा भरोसा कर लें। यदि कोई हस्ताक्षरित चैक गुम हो जाय तो तुरंत बैंक को सूचना दें।

4

अपनी सत्र जमाराशि की निश्चित तिथि याद रखें और यथासमय नवीनीकरण कराना न भूलें।

5

इस बात की ताक़ीद कर लें, कि आपके द्वारा भेजे गये डिमांड ड्राफ़्ट की प्राप्ति सूचना आपको मिल गयी है।

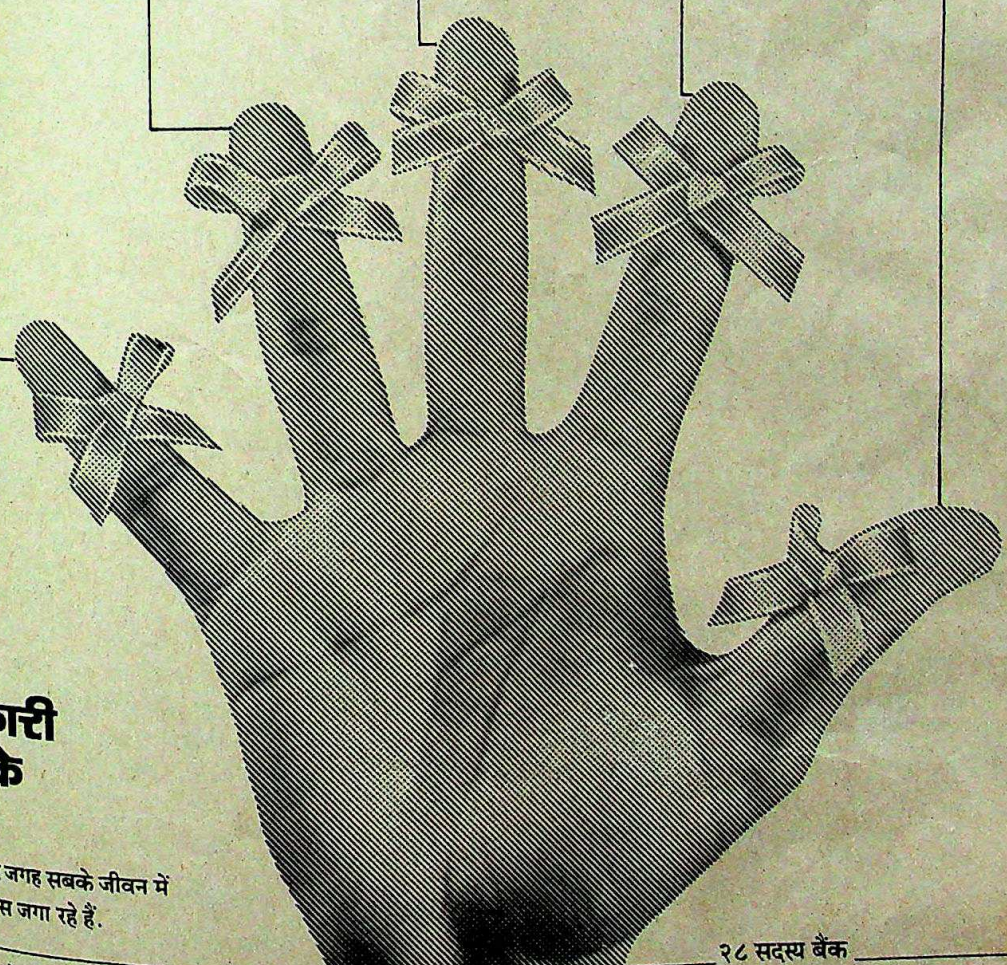

सरकारी क्षेत्र के बैंक

–हर दिन, हर जगह सबके जीवन में नया विश्वास जगा रहे हैं.

संयुक्त प्रचार समिति सरकारी क्षेत्र के बैंक

२८ सदस्य बैंक

- इलाहाबाद बैंक
- आंध्रा बैंक
- बैंक आफ़ बड़ौदा
- बैंक आफ़ इंडिया
- बैंक आफ़ महाराष्ट्र
- कैनरा बैंक
- सैन्ट्रल बैंक आफ़ इंडिया
- कॉर्पोरेशन बैंक
- देना बैंक
- इंडियन बैंक
- इंडियन ओवरसीज़ बैंक
- न्यू बैंक आफ़ इंडिया
- ओरिएण्टल बैंक आफ़ कामर्स
- पंजाब नेशनल बैंक
- पंजाब एंड सिंध बैंक
- स्टेट बैंक आफ़ इंडिया
- स्टेट बैंक आफ़ बिकानेर एंड जयपुर
- स्टेट बैंक आफ़ हैदराबाद
- स्टेट बैंक आफ़ इंदौर
- स्टेट बैंक आफ़ मैसूर
- स्टेट बैंक आफ़ पटियाला
- स्टेट बैंक आफ़ सौराष्ट्र
- स्टेट बैंक आफ़ त्रावणकोर
- सिंडिकेट बैंक
- यूको बैंक
- यूनियन बैंक आफ़ इंडिया
- यूनाइटेड बैंक आफ़ इंडिया
- विजया बैंक

imagepads/IPC/81279 HN

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शीतल पेय में उबाल

लेमन आयल की एक बूंद में जायफल, दालचीनी, चिरायता के जड़ के तेल की थोड़ी मात्रा मिलाएं. फिर नाममात्र को कैफीन, कैरामेल रंग और फास्फोरिक अम्ल मिलाएं. फिर इस मिश्रण की एक छोटी बूंद एक बोतल पानी में रखें. चार चम्मच चीनी मिलाकर उसे फेंट दें. जाहिर है कि बोतल में एक जिन्न ही तैयार होगा. आज इस जिन्न ने देश भर में तहलका मचा रखा है. इसका नाम है पेप्सी कोला.

पेप्सी कोला को भारत में प्रवेश (वोल्टास तथा पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन (पीएआइसी) के साथ मिलकर फल और खाद्य सामग्री की बड़ी योजना) की अनुमति दी जाए या नहीं इस पर भारी शोरशराबा मचा है. और इसके साथ ही खेती, विदेशी मुद्रा की समस्या, बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका, भारतीय लोगों के खाने-पीने की आदतों के भविष्य, भारत में व्यापार की संभावनाओं के बारे में अंतरराष्ट्रीय राय, राष्ट्रीय तकनीकी विकास और पंजाब समस्या के समाधान तक के मुद्दे जुड़ गए हैं. यह सारा बवाल 22 करोड़ रुपए की योजना को लेकर है. यह राशि देश में होने वाले औद्योगिक निवेश का एक फीसदी से भी कम ही है.

"अगर सरकार ने मंजूरी दे दी तो मुझे पक्का भरोसा हो जाएगा कि यहां कोई कानून नहीं चलता और उसे खास लोगों के लिए तोड़ा-मरोड़ा जा सकता है"

रमेश चौहान
अध्यक्ष, पारले एक्सपोर्ट्स

"मैं मानता हूं कि टाटा-मर्सिडीज बेंज गठबंधन ने जिस तरह पूरे इंजीनियरिंग उद्योग को बदल दिया, पेप्सी योजना भी खेती के लिए उतनी ही लाभदायक साबित होगी"

ए.एच. दुबैकोवाला
अध्यक्ष वोल्टास

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

संसद में इस बारे में असंख्य सवाल पूछे जा चुके हैं. 50 सांसदों ने पेप्सी कोला के आने के विरोध में, तो इतने ने ही समर्थन में हस्ताक्षर दिया है. उधर दर्जनों संपादकीय लेख भी आ चुके हैं. इस मुद्दे पर पिछले 20 महीनों में मंत्रिमंडलीय और अंतर-मंत्रालयीय इतनी बैठकें हो चुकी हैं जितनी किसी और समस्या पर नहीं हुई. अभी तक की इन बैठकों में कोई फैसला नहीं हुआ है सो अभी और बैठकें चलनी हैं. इस मुद्दे पर बंबई और कलकत्ता हाईकोर्टों और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी तीखी कानूनी झड़पें हो चुकी हैं. इसी बीच प्रधानमंत्री के एक महत्वपूर्ण सहायक इस योजना को मंजूरी दिलाने के लिए सारा जोर लगाए हुए हैं ताकि राजीव गांधी की राजनैतिक संकल्प शक्ति का परिचय मिल सके.

देश के सबसे प्रतिष्ठित और वरिष्ठ उद्योगपति जे.आर.डी. टाटा ने खुद इस योजना के लिए प्रधानमंत्री और कई मंत्रियों से भेंट की. दूसरी ओर इसके आलोचकों का मानना है कि पेप्सी के भारत में आने से राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी. इससे मौसाईए की घुसपैठ होगी और आलू के चिप्स तथा दूसरी फालतू चीजों के लालच में भारतीयों का स्वास्थ्य बिगड़ेगा.

ऐसा विवाद इस देश में कोई पहली बार नहीं छिड़ा है. दस बरस पहले शेयर होल्डिंग की सीमा और आयात परमिट पर विवाद के बाद कोका कोला यहां से विदा हो गया था. कोका कोला को अमेरिकी तंत्र और उपभोक्तावाद का प्रतीक माना जाता था. सो उसकी विदाई को दुनिया भर के व्यापारियों ने भारत से उपभोक्ता-वाद की भी विदाई मान लिया था.

लेकिन उसके जाने के बाद से इन वर्षों में भारतीय शीतल पेय बाजार चार गुना बड़ा हो चुका है. अब लगता है कि कोला-युद्ध एक चक्कर पूरा कर चुका है. और अब कोका कोला का प्रतिद्वंद्वी पेप्सी कोला (जो 151 देशों में पहुंचकर कारोबार के मामले में कोका कोला को पीछे छोड़ चुका है) भारत में घुसने के रास्ते तलाश रहा है. इसके इस प्रयास पर दुनिया भर के व्यापारियों की नजर ही नहीं लगी है, वे इसके लिए सरकारी दफ्तरों में और बाहर भाग-दौड़ भी कर रहे हैं. इतने लोगों की नजर इस लड़ाई पर लगी हुई है कि पेप्सी का मामला विदेशी कंपनियों के प्रति भारत के नजरिये की परीक्षा का पैमाना बन गया है.

हां, पेप्सी और उसके भारतीय समर्थक यह जरूर कह रहे हैं कि शीतल पेय तो भारत में होने वाले उसके पूरे कारोबार का एक चौथाई ही होगा, कि आधा कारोबार तो पंजाब से फलों के रस के निर्यात का होगा और एक चौथाई आलू के चिप्स तथा दूसरे तैयार खाद्य पदार्थों को देसी बाजार में बेचने का.

इस योजना के बारे में बड़े-बड़े दावे जरूर किए जा रहे हैं. मसलन यह हरित क्रांति के बाद भारतीय खेती के क्रांतिकारी विकास में मदद देगा; मुनाफे वाली बागवानी के मामले में क्रांति लाएगा; फलों के रस के निर्यात से पंजाब और आसपास के राज्यों के किसान मालामाल हो जाएंगे; पेप्सी खेती की नवीनतम तकनीक किसानों तक पहुंचाएगा; पंजाब में रोजगार-धंधे के अवसर इतने बढ़ेंगे कि आतंक-वादी समस्या सुलझाने में भी मदद मिलेगी; निर्यात बढ़ने की संभावना इतनी अधिक है कि इससे भारत की विदेशी मुद्रा की समस्या भी सुलझ सकती है. और न जाने और क्या-क्या हो जाएगा. और देशों में पेप्सी के जाने से क्या नाटकीय बदलाव हुए हैं, इसके उदाहरण भी गिनाए जाते रहे हैं.

इनमें से अनेक दावों को सबूतों से साबित करना मुश्किल है और इनमें से कई बढ़ा-चढ़ाकर की गई बातें भी हैं. लेकिन वोल्टास के अध्यक्ष ए.एच. टुबैकोवाला कहते हैं, "मैं पक्के तौर पर मानता हूं कि टाटा-मर्सिडीज बेंज गठबंधन ने जिस तरह पूरे इंजीनियरिंग उद्योग को बदलकर रख दिया, पेप्सी योजना भी खेती के लिए उतनी ही लाभदायक साबित होगी. अगर इस योजना को मंजूरी मिली तो यह भारतीय कृषि के स्वरूप को ही बदल देगी."

टुबैकोवाला इस योजना के (जो चीन या सोवियत संघ के मुकाबले बेहतर शर्तों पर होगी) फायदों के बारे में इतने आश्वस्त हैं कि उनका मानना है कि भविष्य में विदेशी गठबंधनों के लिए इसे ही मॉडल बनाना चाहिए. वे बागवानी के विकास में पेप्सी की तकनीक लेने की वकालत करते हैं. उनका कहना है कि हरित क्रांति भी विदेशी तकनीक से ही आई थी.

व्यापार विकास के लिए पेप्सी कोला के अंतरराष्ट्रीय निदेशक रमेश वांगल कहते हैं कि भारत सरकार इतने आकर्षक प्रस्ताव को 'झपट' नहीं ले रही है इसी से पेप्सी के

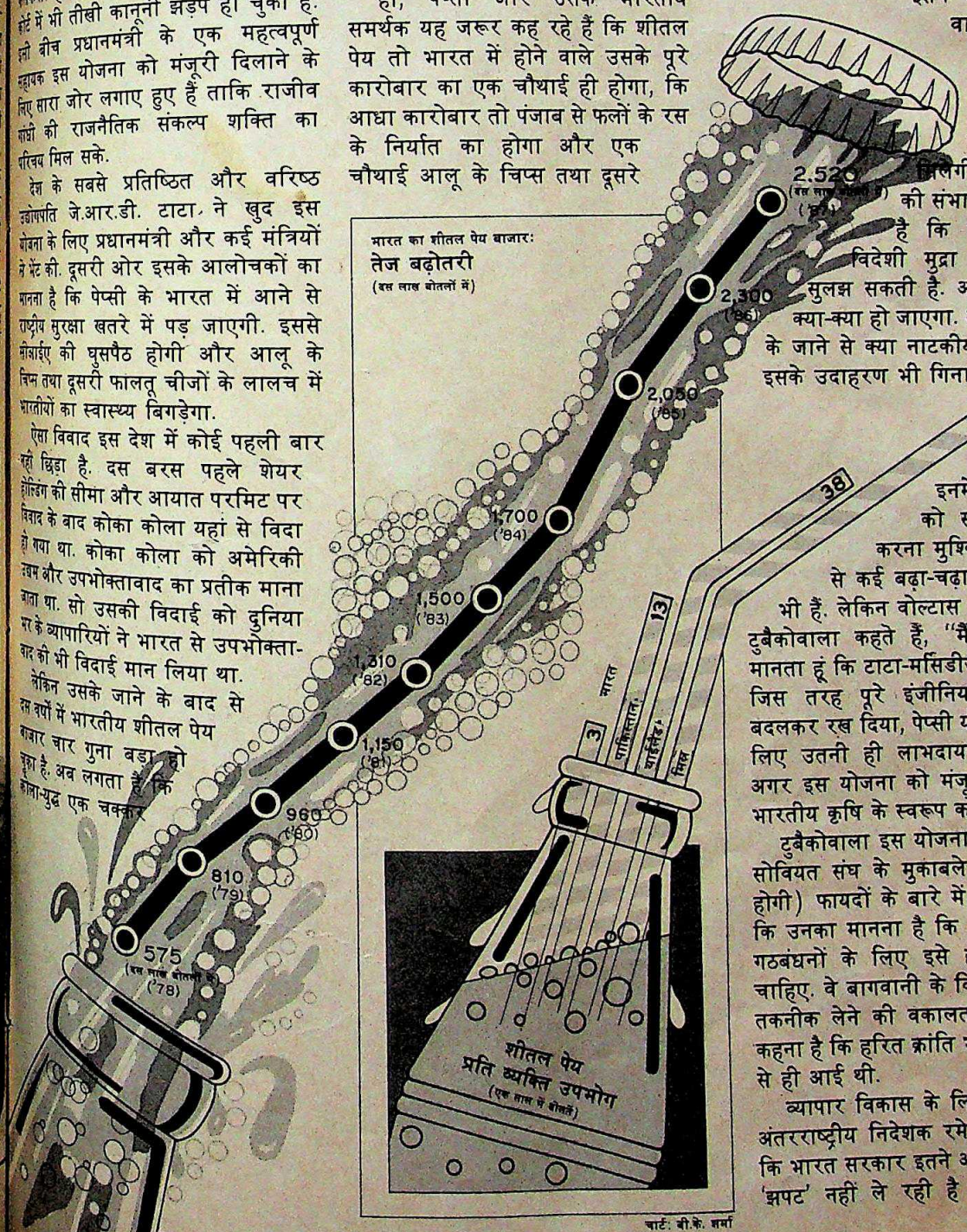

चार्ट: बी.के. शर्मा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

5-YEAR REVIEW HIGHLIGHTS REMARKABLE GROWTH

Excerpts from the speech of Mr Surrendra Paul, Chairman, Assam Frontier Tea Limited, at the 10th Annual General Meeting held on December 4, 1987 at Talap, Assam.

I welcome you all to the 10th Annual General Meeting to consider and approve the Annual Report and Accounts for the year ended June 30, 1987.

The Company's growth over the last five years has been most impressive, and is a culmination of the policies adopted and the inputs provided over these years to make it a great tea Company.

In the period since this Management took over the Company, gross block has gone up from Rs. 657 lakhs in 1981-82 to Rs. 1636 lakhs last year. Turnover in 1981-82 was Rs. 1559 lakhs and pre-tax profit was just Rs. 56 lakhs ; in 1986-87 turnover is Rs. 3390 lakhs and profit before tax is Rs. 702 lakhs. Reserves have multiplied over 9 times, from Rs. 74 lakhs to Rs. 685 lakhs. Earning per share is Rs. 11.36, enabling us to recommend a dividend of 50%. With this, the Company, in 5 years, has paid out a total dividend of 188%.

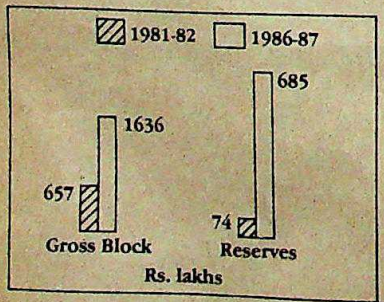

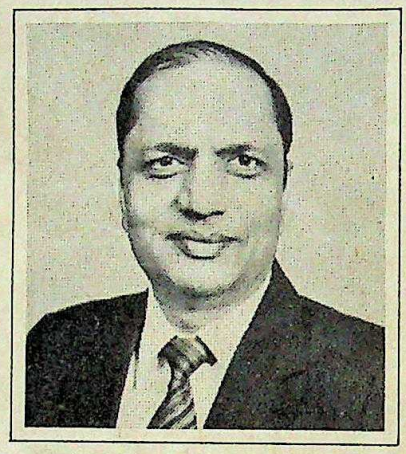

Mr. Surrendra Paul

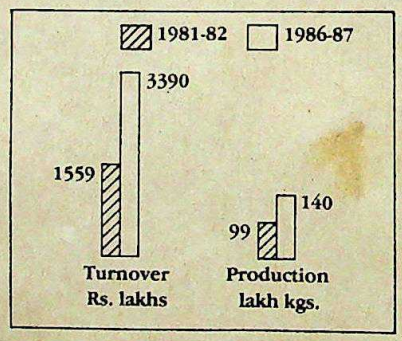

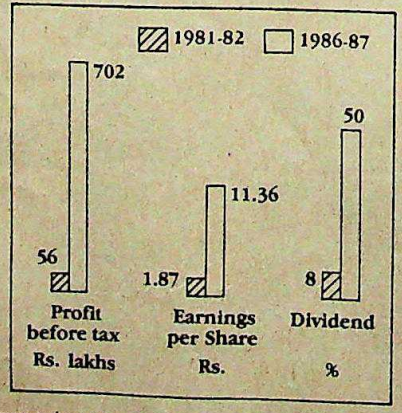

Production in 1987 is estimated to be 140 lakh kgs, compared to 99 lakh kgs in 1982, an increase of over 41%. 870 hectares were brought under extension planting in this period.

The Company's produce traditionally finds widespread acceptance in international markets. More than half of the tea grown in our gardens is directly or indirectly exported, and we are trying to export a larger percentage of this directly.

Clear thinking and dedicated hard work have gone into achieving these results. And I know that the General Manager, the Managers, Assistants and workers are as pleased with the fruits of their dedication as I am. I thank them all. I also thank the Board of Directors for their guidance and the Head Office in Calcutta for their support.

The future

As you can see, the induction of specialised managerial skills and the infusion of massive financial investments has yielded good results. With upgraded facilities, new plant and equipment, machinery and buildings, we are now geared to achieve even higher production of quality tea. *We have committed ourselves to doubling the 1982 crop in the next 5 years, with quality equivalent to the best.*

An Apeejay update

In 1987 APEEJAY celebrated 20 years of hoteliering by opening a hotel in New Delhi. Link by link, the best located luxury hotels chain is growing—Calcutta, Visakhapatnam, New Delhi and soon in Bombay.

The gas based Fertilizer Plant at Shahjahanpur, U.P. has not gained momentum, but the project is still in hand and we look forward to making substantial progress in 1988.

Note: This does not purport to be a report of the proceedings of the Tenth Annual General Meeting.

ASSAM FRONTIER

ASSAM FRONTIER TEA LIMITED

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कर्ताधर्ता हैरान हैं. वे कहते हैं, "अगर ऐसा प्रस्ताव हमने दुनिया के किसी और देश के सामने रखा होता तो वे एकबारगी खुशी से उछल ही पड़ते."

लेकिन देश की सबसे बड़ी शीतल पेय कंपनी पारले एक्सपोर्ट्स के अध्यक्ष रमेश चौहान को लगता है कि निर्यात और कोला से इतर मुद्दों के मामले में सब्जबाग दिखाकर भारतीय लोगों को भरमाया जा रहा है. वे इन मुद्दों से सहमत नहीं हैं. उनका कहना है, "अगर सरकार ने इस योजना को मंजूरी दे दी तो मुझे यह पक्का भरोसा हो जाएगा कि यहां कोई कानून नहीं चलता और उसे खास लोगों की सुविधा के लिए तोड़ा-मरोड़ा जा सकता है." अनेक प्रेक्षकों का मानना है कि यह मामला सीधे-सीधे एक कोला कंपनी के भारतीय बाजार में प्रवेश का है, और कुछ नहीं.

अगर भारत सरकार इस पर अभी तक अपना मन नहीं बना पाई है तो इसका कारण इस योजना से जुड़े विवादास्पद मुद्दे ही हैं. पेप्सी की शर्तें कोका कोला से निश्चित रूप से बेहतर हैं—देसी कंपनियों (वोल्टास और पीएआइसी) के पास अधिकांश शेयर होंगे, दस वर्ष में फलों के रस और दूसरे खाद्य पदार्थों के निर्यात से करीब 200 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की कमाई होगी, इस योजना में जितना आयात होगा उसका पांच गुना निर्यात होगा, पेप्सी कृषि की वैसी नई तकनीक ले आएगा जिसके सहारे मेक्सिको में आलू की पैदावार तीन वर्षों में दुगुनी करने का दावा किया जाता है और देसी कोला बाजार में एक कंपनी का एकाधिकार टूटेगा.

दूसरी ओर शीतल पेय जैसे गैर-प्राथमिकता वाले उद्योग में बहुराष्ट्रीय कंपनी की घुसपैठ पर जायज सवाल उठाए जा रहे हैं. कहा जा रहा है कि कोका कोला के जाने के बाद देसी कंपनियों ने इतनी अच्छी प्रगति की है तो बाहरी कंपनी को क्यों बुलाया जाए. देसी बाजार चौगुना होने के साथ ही पारले ने पश्चिम एशिया, नाइजीरिया और दूसर देशों को निर्यात करना भी शुरू कर दिया है. साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि पेप्सी निर्यात के जैसे वायदे कर रही है वैसे पहले भी हो चुके हैं, पर विदेशी मुद्रा के मामले में स्थिति सुधरी नहीं. और फिर चौहान के अनुसार पेप्सी का प्रस्ताव विदेश व्यापार संबंधी जटिल सरकारी नियमों के अनुकूल नहीं है.

यानी कुल मिलाकर मुख्य आपत्ति यह है कि बहुराष्ट्रीय निगम को प्रवेश देकर निर्यात बाजार में प्रवेश कर रही देसी कंपनियों के कारोबार को क्यों प्रभावित किया जाए. यह भी माना जा रहा है कि निर्यात और कृषि तकनीक वगैरह की सारी हवाई बातें सिर्फ शीतल पेय बाजार में घुसपैठ के लिए ही की जा रही हैं.

सरकार अब तक यह तय नहीं कर पाई है कि कौन-सा तर्क सही है. सबसे कड़ा विरोध खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय ने किया है. उसका कहना है कि भारत को फलों के रसों को बढ़ावा देना चाहिए न कि रासायनिक पेयों को. वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने भी विरोध किया है. चूंकि उसने खुद शीतल पेय का फ्लेवर तैयार किया है इसलिए उसका कहना है कि इसके लिए विदेशी गठजोड़ की क्या जरूरत है.

पर अनेक दूसरे विभाग इस प्रस्ताव की जोरदार वकालत कर रहे हैं. एक बार तो मंत्रालय ने यह शिकायत भी की थी कि इस मुद्दे पर उसकी राय को बैठक के विवरण में भी दर्ज नहीं किया जाता. एक बार तो प्रस्ताव रखने वालों से कहा गया कि क्या

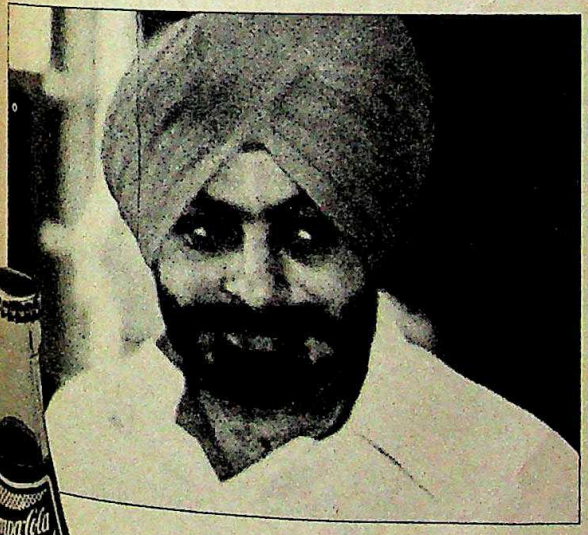

चरणजीत सिंह के प्योर ड्रिंक्स का शीतल पेय के एक चौथाई बाजार पर ही कब्जा है. अभी तक वह रमेश चौहान के पारले से काफी पीछे रहते हुए दूसरे स्थान पर है और सिर्फ दिल्ली में बाकियों से ही वह आगे है

विजय माल्या की लाख कोशिशों के बावजूद उनके 'थ्रिल' और दूसरे ब्रांडों को 10 फीसदी बाजार ही मिला है. अगर पेप्सी और पारले की भिड़ंत हुई तो छोटी कंपनियां मारी जाएंगी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आप कोला वाली योजना छोड़कर सिर्फ फलों के रस और आलू के चिप्स वाला प्रस्ताव नहीं रख सकते तो फिर जवाब मिला, 'नहीं'. हां, प्रस्ताव रखने वालों ने निर्यात की पूर्वशर्त में 65 फीसदी तक बढ़ोतरी और शीतल पेय के कुल कारोबार का 25 फीसदी तक सीमित रखना मंजूर कर लिया था.

फिर पिछले साल के आखिर में योजना मंजूरी बोर्ड की बैठक हुई और उसने नवीनतम संशोधनों पर विचार करके प्रस्ताव को मंत्रिमंडल समिति के पास भेज दिया. फरवरी के शुरू में जब इन मंत्रियों की बैठक हुई तो सारे लोग दम साधे हुए फैसले की प्रतीक्षा कर रहे थे. 8 फरवरी की बैठक की अध्यक्षता गृहमंत्री बूटा सिंह ने की. बैठक में वित्तमंत्री नारायणदत्त तिवारी, उद्योगमंत्री जे. वेंगलराव, तत्कालीन कृषि और ग्रामीण विकास-मंत्री गुरदयाल सिंह ढिल्लों और तत्कालीन खाद्य और आपूर्तिमंत्री हरिकिशनलाल भगत भी शामिल हुए.

पेप्सी का कारखाना पंजाब में लगाने का प्रस्ताव है और बूटा सिंह तथा ढिल्लों यही चाहते थे. लेकिन भगत इसके सख्त खिलाफ थे. वेंगलराव का रुख स्पष्ट नहीं था. उन्होंने शुरू में एक बार प्रस्ताव रखने वालों में से एक से कहा था, "50 सांसदों ने प्रस्ताव के विरोध में ज्ञापन दिया है. आपके पक्ष में कोई नहीं है. मैं क्या कर सकता हूं?"

निश्चित रूप से पेप्सी वाले मुद्दे पर अनेक सांसद बहुत सक्रिय रहे हैं. महाराष्ट्र के इक्का

विदेशी ब्रांड नाम

कानून-कायदा ताक पर

शुरुआत बड़ी धीमी गति से हुई. विदेशी ब्रांडों में पहले रॉथमैंस और फिर चेस्टरफील्ड्स सिगरेटें आईं. इसके बाद रफ्तार तेज हो गई. तब टैंग शीतल पेय पाउडर और इंग्लिश लेदर श्रृंगार प्रसाधन भी चले आए. और अब तो जैसे बाढ़ ही आ गई है: बार्बी डॉल्स, अमेरिकन टूरिस्टर लगेज, रैंगलर और प्लेब्वॉय कपड़े, डबल कोला...सूची है कि लंबी ही होती जाती है. उधर नाइक और एडीडास जैसे नाम भी आने को तैयार बैठे हैं.

देश के समृद्ध लोगों के नाम और क्वालिटी के पीछे दीवाने होने का लाभ उठाते हुए देशी बाजार में विदेशी ब्रांडों की भरमार हो रही है.

सरकार की यह नीति है कि भारत में किसी विदेशी ब्रांड नाम के इस्तेमाल की अनमुति नहीं दी जाए. इसके बजाय जापान के सोनी और टोयोटा की तरह देसी ब्रांड नाम की धाक जमाई जाए. सरकार विदेशी गठबंधनों की अनुमति देते समय (पिछले साल ऐसे 900 गठबंधन हुए) उन्हें विदेशी ब्रांड नाम इस्तेमाल न करने की शर्त लगाती है. पेप्सी कोला के भारत में प्रवेश का आवेदन देने से पहले ही उससे वह शर्त मनवा ली गई थी. पेप्सी कोला पर विवाद में ब्रांड नाम का झगड़ा अलग ही रहा.

लेकिन सरकार और उद्योग जगत के जानकार लोग भी पा रहे हैं कि हर कानून में कोई पेंच छूट ही जाता है. और विदेशी ब्रांड नामों पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को आज इस आसानी से लांघा जा सकता है कि यह एक मजाक का विषय बन गया है.

ब्लो प्लास्ट कंपनी के दिलीप पीरामल ने मैट्टेल से अमेरिकन बार्बी डॉल्स बनाने और बेचने का करार किया. फिर वे विदेशी ब्रांड नाम का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? उनका जवाब है कि बार्बी उनका कोई ब्रांड नाम नहीं है. यह तो मैट्टेल द्वारा बनाई जाने वाली गुड़िया का नाम है. पीरामल के उत्पादन का ब्रांड नाम तो लियो-मैट्टेल है. पर इस नाम का उपयोग कोई नहीं करता. पीरामल जोर देकर कहते हैं, "हमने कोई कानून नहीं तोड़ा है."

भारत में घुसपैठ करने वाला दूसरा ब्रांड नाम है अमेरिकन टूरिस्टर. गुजरात बी.डी. लगेज के उत्पादन को इसी नाम से जाना जाता है. पर उसका असली नाम 'हालमार्क' है. कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक एल.डी. थवाणी का दावा है कि अमेरिकन टूरिस्टर नाम का इस्तेमाल सिर्फ गठबंधन का प्रचार करने के लिए किया गया. ग्राहकों पर इतना ही असर हुआ होगा ऐसा नहीं लगता.

इस बीच जे.बी. आडवाणी ऐंड कंपनी (मैसूर) ने बंगलूर के अपने प्लांट में इंग्लिश लेदर नामक पुरुष सौंदर्य प्रसाधन बनाना शुरू करके हंगामा मचा दिया है. विदेशी ब्रांड नाम का इस्तेमाल वे कैसे कर रहे हैं, यह पूछे जाने पर लालवाणी ने कहा कि कानून में उन्होंने किस तरह पेंच निकाला है. यह 'कंपनी सीक्रेट' है.

दूसरे लोग इस मामले में एकदम स्पष्ट रूप से बताते हैं कि उन्होंने क्या तरीका अपनाया. मद्रास की कोठारी जनरल फूड्स कंपनी अमेरिकी जनरल फूड्स कंपनी का ब्रांड नाम 'टैंग' का इस्तेमाल करती है. उसका कहना है कि अमेरिकी कंपनी ने बिना कोई पैसा लिए उसे यह नाम दिया है.

रैंगलर का प्रवेश तो आप्रवासी भारतीय वाले 'रूट' से हुआ. बंबई की कंपनी डयूपोंट स्पोर्ट्सवियर ने अमेरिकी कपड़ा कंपनी से

विदेशी नामों का धड़ल्ले से प्रयोग

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सांसद सुरेश कलमाडी ने इस मामले पर संसद में दर्जनों सवाल पूछे हैं. धरमचंदर प्रभात भी बहुत पीछे नहीं होंगे. आनंद पाठक जैसे दूसरे सदस्य भी काफी सक्रिय रहे हैं. कलमाडी ने कहा, "मैं प्रतिद्वंद्विता के खिलाफ नहीं हूं. मुझे मालूम है कि शीतल पेय बाजार में प्रतिद्वंद्विता की जरूरत है पर यह बिना विदेशी ब्रांड नाम के भी चल सकती है."

इस प्रस्ताव का सबसे सख्त विरोध किया है इंका महासचिव केदारनाथ सिंह ने, "वे कोला की बाहरी टीमटाम दिखाते हुए आए हैं, पर उनका असली इरादा साम्राज्यवादी ताकतों का मतलब साधना है. क्या हमें देश की सुरक्षा की कीमत पर शीतल पेय की जरूरत है?" लेकिन प्रस्ताव की उतनी ही जबरदस्त वकालत की पंजाब के राज्यपाल सिद्धार्थ शंकर राय ने, "पंजाब में सिर्फ कानून और व्यवस्था की समस्या ही नहीं है. इसके अनेक आर्थिक पहलू भी हैं. आतंकवादी गतिविधियों के लिए जिन युवकों को पकडा गया है, उनमें अधिकांश बेरोजगार हैं. पेप्सी योजना से इन लोगों को काम मिलेगा और पांच एकड़ की जोत वाले किसान भी साल में कम-से-कम 50,000 रुपए कमा सकेंगे."

पर अदालतों में चला विवाद खास तौर से तीखा था. जैसे ही पेप्सी कोला द्वारा भारत में कारोबार शुरू करने में दिलचस्पी लेने की खबरें आने लगीं, वैसे ही 'एक्सप्रेस बॉटलर्स' नामक अज्ञात कंपनी ने अदालत में दावा किया कि पेप्सी ब्रांड नाम उसका है और करार किया. ड्यूपोंट के अध्यक्ष अशोक बातान कहते हैं कि रैंगलर को इस करार से कुछ भी नहीं मिलेगा (अगर पैसा नहीं देना पड़े तो सरकार ब्रांड नाम का इस्तेमाल करने से रोक नहीं सकती).

अमेरिकी झंडे को भी अपने विज्ञापन की पृष्ठभूमि में इस्तेमाल करने वाले डबल कोला का किस्सा कुछ और तरह का है. एक प्रवासी भारतीय (वी.सी. कुमारन) ने डबल कोला बनाने वाली मूल अमेरिकी कंपनी को ही खरीद लिया. अब कुमारन ने भारत में कंपनी खोल ली है. चूंकि विदेश में उन्हीं की कंपनी है इसलिए वे भारत में भी बिना अनुमति के अपनी कंपनी के उस ब्रांड नाम का उपयोग कर सकते हैं.

पर सबसे अजीब मामला रॉथमैंस का है. शुरू में इसे डंकन एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड बेचा करती थी. मजेदार बात यह है कि अब डंकन कंपनी के मालिक गौरी प्रसाद गोयनका इसे सिगरेट फिल्टर बनाने वाली बंगलूर की छोटी कंपनी 'स्विस-इंड' के हवाले कर चुके हैं. इस छोटी कंपनी में एक विदेशी शेयर होल्डर थे, बॉमगार्टनर जिन्हें स्विस-इंड के अपने 40 फीसदी शेयर रॉथमैंस को बेचने के लिए 'मना' लिया गया. और इस प्रकार इस छोटी कंपनी में विदेशी शेयर होल्डिंग से एक दक्षिण अफ्रीकी सिगरेट कंपनी को भारत में प्रवेश मिल गया. रॉथमैंस डंकन कंपनी बनाती है और स्विस-इंड वितरित करती है.

प्लेब्वॉय ने ब्रांड नाम की समस्या बसे अधिक आजमाए तरीक से सुलझाई. उसने इसमें एक भारतीय नाम भी जोड़कर इसे प्लेब्वॉय-फैशन स्कोर्ट बना दिया. ऐसे ही नाम कावासाकी-बजाज, काइनेटिक-होंडा, मारुति-सुजुकी, राजदूत-यामाहा और कई दूसरे हैं.

विदेशी नामों का उपयोग करने का लालच कई वाजिब कारणों से है. बंगलूर में डबल कोला का उत्पादन करने वाले वी.के. विजय कुमार कहते हैं, "बिक्री उम्मीद से अच्छी रही है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय ब्रांड नाम को देखकर लोगों को अच्छी क्वालिटी का भरोसा हो जाता है."

और सिगरेट को छोड़कर बाकी सभी मामलों में विदेशी ब्रांड नाम वाले उत्पादनों ने बढ़िया कारोबार किया है. रॉथमैंस, एकदम पिट गया है और कृष्णकुमार मोदी के गॉडफ्रे फिलिप्स के कारोबार में चेस्टर-फील्ड्स का हिस्सा मात्र दो फीसदी है. लेकिन इंग्लिश लेदर और अमेरिकन टूरिस्टर का कारोबार बहुत बढ़िया रहा है. बार्बी डॉल्स और टैंग की बिक्री थोड़ी कम रफ्तार से हुई है. लालवाणी बताते हैं, "भारतीय लोगों को हर विदेशी माल पसंद है. अगर विदेशी न हो तो विदेशी जैसा लगना चाहिए. और ब्रांड नाम से यह बात आ जाती है." और उन्हें इस बात में संदेह नहीं कि अगर वे अपने उत्पादन का नाम इंग्लिश लेदर नहीं रखते तो उनके माल की इतनी बिक्री नहीं होती.

विदेशी ब्रांड नाम वाली अधिकांश चीजें अमीर लोगों को ही ध्यान में रखकर लाई जा रही हैं जो बार्बी डॉल्स के लिए 100 रुपए से अधिक, एक ब्रीफकेस के लिए 690 रुपए और एक रैंगलर जींस के लिए 750 रुपए देने को तैयार हैं. अपवाद सिर्फ मदरकेयर है. उसका मानना है कि विदेशी ब्रांड नाम वाली चीजें बाद में कम आय वाले लोगों के मन में भी जगह बनाएंगी और फिर ऐसी चीजों का उत्पादन बड़े पैमाने पर करना होगा.

लेकिन पेप्सी की नाराजगी इसी बात को लेकर है कि जब कई रास्तों से देश में इतने सारे विदेशी ब्रांड नाम घुस आए हैं तो फिर उसी के नाम पर आपत्ति क्यों. वैसे पारले के रमेश चौहान का मानना है कि किसी भी विदेशी ब्रांड नाम को अनुमति नहीं मिलनी चाहिए. और अभी तो नहीं लगता कि सरकार कुछ करने जा रही है.

—टी.एन. नाइनन, सलिल त्रिपाठी, अनीता प्रताप और ब्यूरो रिपोर्ट

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पेप्सी कोला का दावा गलत है. अब कलकत्ता, बंबई और दिल्ली में अदालती लड़ाई चल रही है. पेप्सी कोला इंटरनेशनल अभी तक अपने ब्रांड नाम के दुनिया भर में इस्तेमाल के दावे को बहुत मजबूती से नहीं उठा पाया है लेकिन इसने दूसरे तरीके से असली मुद्दे को उठाया है. इसने साबित किया (और अदालत में कहा है) कि एक्सप्रेस बॉटलर्स पारले के रमेश चौहान से जुड़ी कंपनी है. इसके पते की जगह पारले के निदेशक आइ.एन. मुंगाले का पता लिखा है और इसके अधिकांश शेयर होल्डर पारले कंपनी का माल बोतलबंद करने वाली कंपनियां ही हैं.

कंपनियों को अपना पेय बोतलबंद करने का अधिकार देकर उन्होंने देश भर पर अपना 'राज' कायम कर लिया है. निजी बातचीत में पेप्सी वाला प्रस्ताव रखने वाले लोग भी मानते हैं कि देरी की एक वजह तो चौहान द्वारा प्रभावी ढंग से इस योजना का विरोध करना भी है.

अब महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर सरकार ने पेप्सी को अनुमति दे दी तो 'दादा' कौन साबित होगा. पीएआईसी, वोल्टास (जिनके 25-25 फीसदी शेयर होंगे) और पेप्सी (जिसके 40 फीसदी शेयर होंगे) का मानना है कि अभी तक बाजार पर चौहान

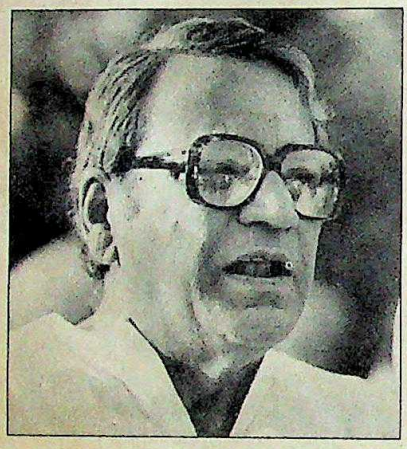

"पंजाब में सिर्फ कानून और व्यवस्था की समस्या ही नहीं है. जिन युवकों को पकड़ा गया है, उनमें से अधिकांश बेरोजगार हैं. पेप्सी योजना से इन लोगों को काम मिलेगा"

सिद्धार्थशंकर राय,
राज्यपाल, पंजाब

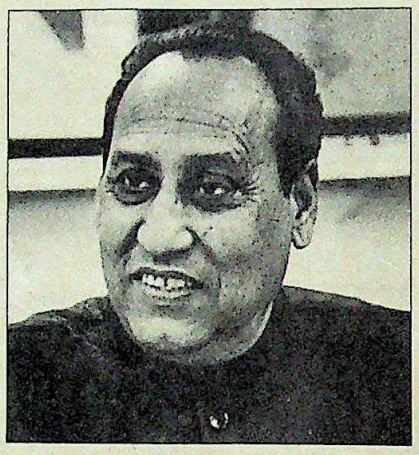

"वे कोला की टीमटाम दिखाते हुए आए हैं पर उनका असली इरादा साम्राज्यवादी मतलब साधना है. क्या देश की सुरक्षा की कीमत पर शीतल पेय की जरूरत है"

केदारनाथ सिंह
महासचिव, इंका

पर इस पूरी लड़ाई का एक पहलू यह भी है कि एक ओर तो पेप्सिको (कारोबार 48,000 करोड़ रु.), टाटा समूह (कारोबार 4000 करोड़ रु.) और पंजाब सरकार की अपनी पीएआईसी है जबकि दूसरी ओर लघु उद्योग के रूप में पंजीकृत पारले के चौहान हैं. इस शीतल पेय कंपनी के कांसट्रेट के वार्षिक बिक्री 15 करोड़ रुपए की है.

जहां तक 600 करोड़ रुपए के देसी शीतल पेय बाजार की बात है, चौहान ही उसके 'दादा' बने हुए हैं (पारले के थम्स अप, लिम्का वगैरह ने करीब 50 फीसदी बाजार पर कब्जा कर रखा है). और 62 के कब्जे के कारण सही प्रतिद्वंद्विता नहीं हो पा रही थी और बाजार भी फैल नहीं रहा था. भारत में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष तीन बोतल शीतल पेय ही खपता है जबकि पाकिस्तान में 12 बोतल और दूसरे देशों में और भी अधिक खपत है.

पेप्सी कोला वाला तिगुटा चौहान को एक चालाक पर बाजार को तेजी से न बढ़ा पाने वाला व्यापारी मानता है. पारले का पेय बोतलबंद करने वाली अनेक छोटी कंपनियां चौहान के व्यवहार से दुखी बताई जाती हैं. इसलिए हो सकता है कि वे पेप्सी से जुड़ जाएं. दूसरी ओर चौहान 458 करोड़ रुपए कारोबार वाली वोल्टास और पीएआईसी को मजबूत नहीं मानते. दोनों का वोलटर्स बाजार में जम नहीं पाया. इसलिए उनका मानना है कि ये पेप्सी के लिए बोझ ही बन जाएंगी.

लेकिन दोनों ही पक्ष मानते हैं कि उन्हें एक-दूसरे से निबटने में मुश्किल होगी. पेप्सी के रमेश वांगल ने दिल्ली में अपने प्रस्ताव की पैरवी करने के वक्त ही कुछ समय निकाल कर देश के दर्जनों शहरों और गांवों की यात्रा की. वे बाजार के बारे में अनुमान लगाते, विपक्षी की कमजोरी का पता लगाने और अनुमति मिलने के बाद की असली लड़ाई की तैयारी करते रहे.

पेप्सी के आने से सबसे अधिक प्रभावित कौन होगा—चौहान या उनके दर्जनों छोटे प्रतिद्वंद्वी? अभी तो चौहान की स्थिति बहुत मजबूत है. चरणजीत सिंह के 'प्योर ड्रिंक्स' का एक चौथाई बाजार पर ही कब्जा है जबकि विजय माल्या के 'थ्रिल' और दूसरी कंपनियों का 10 फीसदी से भी कम हिस्सा है. छोटी कंपनियों और बोतलबंद करने वालों का शेष भाग पर कब्जा है. अभी तक चरणजीत सिंह तो चौहान से काफी पीछे रहते हुए दूसरे स्थान पर हैं. सिर्फ दिल्ली में वे पहले नंबर पर हैं. माल्या ने भी अपने ब्रांडों के सहारे बाजार में जमने की काफी कोशिश की. पर ऐसा हो नहीं पाया. चौहान का तर्क है कि पारले और पेप्सी की लड़ाई में छोटी कंपनियां मारी जाएंगी.

और निश्चित तौर पर पेप्सी अपने एक सबसे बड़े हथियार—ब्रांड नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकेगी. उसने सरकार से वायदा कर रखा है कि वह अपने नाम को किसी भारतीय नाम में उपसर्ग के तौर पर ही जोड़ेगी और ऐसा नाम टाटा-पेप्सी या इंड-पेप्सी जैसा कुछ हो सकता है. पर इसमें गड़बड़ी ही रहेगी. टुबैकोवाला कहते हैं, "मैं कॉलगेट टूथपेस्ट, चेस्टरफील्ड्स सिगरेट और यहां तक कि डबल कोला और टैंग भी खरीद सकता हूं. हमारी योजना में खाद्य और फल निर्यात है पर इन चीजों को ऊंची प्राथमिकता वाला मान लिया गया. हमारे प्रस्ताव में 50 फीसदी निर्यात की पूर्व शर्त है जबकि भारत में ही निर्यात की बिना किसी पूर्व शर्त वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां काम कर रही हैं. पर वे अपने ब्रांड नाम का इस्तेमाल कर सकती हैं जबकि हम नहीं कर सकते."

लेकिन ब्रांड नाम न मिलने के बाद भी पेप्सी शीतल पेय बाजार में जबरदस्त ताकत के साथ उतरेगी. और अगर इस योजना को अंतिम मंजूरी मिल गई तो धूम-धड़ाके के साथ असली कोला-युद्ध की शुरुआत होगी.

—टी.एन. नायन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कंप्यूटर कंपनियों का 'मक्का'

भारत एकाएक दुनिया भर के कंप्यूटर से जुड़े लोगों के लिए जैसे मक्का बन गया है. और इस तीर्थ यात्रा पर आने वालों की कतार में अब खड़ी हैं दो प्रमुख अमेरिकी कंपनियां—हिवलेट पैकर्ड (एचपी) और वैंग लेबोरेटरीज. एचपी ब्लू-स्टार कंपनी के सहयोग से बंगलूर में कंप्यूटर और टेस्टिंग उपकरण बनाने की योजना बना रही है. इस बीच वैंग कई तरह के वैंग कंप्यूटर बनाने की 20 करोड़ रुपए की योजना पर ओबेराय समूह से बात चला रही है. इन दो योजनाओं पर काम शुरू हो गया तो ये कंपनियां भारत आने के लिए कतार में खड़ी दूसरी दिग्गज विदेशी कंप्यूटर कंपनियों में अव्वल हो जाएंगी. इनमें फ्रांस की बुल, पश्चिम जर्मनी की निक्सडोर्फ और अमेरिका की अपोलो कंप्यूटर्स तथा डिजिटल इक्विपमेंट कार्पोरेशन शामिल हैं. देश में कंप्यूटर उद्योग का विकास सालाना 40 फीसदी की दर से हो रहा है.

रौब नहीं पड़ता

जो कंपनियां विदेशी गठबंधन का शोर मचाती शेयर बाजार में उतर रही हैं, उनमें से कुछ के शेयर बुरी तरह पिटे हैं. निवेशक देसी भागीदारों के पिछले रिकार्ड को ज्यादा महत्व देते हैं. पर वे शेयरों में पैसा लगाने को अभी भी जोखिम भरा काम मानते हैं. ये नतीजे मार्केटिंग ऐंड बिजनेस एसोसिएशन की सहयोगी साइंस रिसर्च सर्विस ने 20 शहरों की निवेश प्रवृत्ति के अध्ययन से निकाले हैं. एजेंसी ने 2500 रुपए महीने से ज्यादा आमदनी वाले 6000 परिवारों का सर्वेक्षण किया जिनमें से दो तिहाई निवेशक थे. यह सर्वेक्षण एक बैंक ने कराया था. सर्वेक्षण के दूसरे नतीजे थे: अधिकांश लोगों को यूनिट ट्रस्ट के मास्टर शेयर के बारे में पता नहीं था पर 'इंदिरा विकास पत्र' की जानकारी थी.

चल अंकल सैम के देश

भारतीय वाहन निर्माता क्या गलाकाट स्पर्धा वाले अमेरिकी बाजार में जनरल मोटर्स, क्राइसलर, फोर्ड और जापान की टोयोटा जैसी कंपनियों का मुकाबला कर सकते हैं. कुछ साल पहले तक तो लोग इस सवाल को यों ही उड़ा देते. पर अब ऐसा नहीं है. टाटा समूह ने अमेरिकी बाजार में हल्के ट्रक भेजने की तैयारी कर ली है और महिंद्रा ऐंड महिंद्रा की जीपें भी वहां पहुंचने वाली हैं. 'टेल्को' अमेरिकी बाजार के अध्ययन में लगा है. वैसे अभी कीमत वगैरह जैसे मसले तय नहीं हुए हैं पर दो साल के अंदर 'टेल्को' के कुछ ट्रक अमेरिकी सड़कों पर दौड़ने लगेंगे. टाटा को उम्मीद है कि बाद में ट्रकों का निर्यात बढ़ सकेगा. कोरिया की हयूंडाई कंपनी ने भी अमेरिकी बाजार में अच्छी पकड़ बनाई है.

पढ़ने को मिलेगा

अब रेल यात्री भी हवाई यात्रियों की श्रेणी में शामिल होने जा रहे हैं. अगले मई महीने से रेलवे अपने प्रथम श्रेणी के यात्रियों को 64 पेज की पत्रिका मुफ्त दिया करेगी. ऐसा सिर्फ 20 तेज रफ्तार गाड़ियों में ही होगा. इंडियन एअरलाइंस के लिए 'स्वागत' नाम की पत्रिका छापने वाली हांगकांग स्थित प्रकाशन संस्था, ट्रांस एशिया मीडिया ही इस पत्रिका की करीब 2.50 लाख प्रतियां मुफ्त छापा करेगी. वह इसमें छपे विज्ञापनों का पैसा ले लिया करेगी. यात्री चाहें इस पत्रिका को घर भी ले जा सकते हैं.

रीता हो रहा भंडार

जैसा अंदेशा था, सूखे ने देश के अनाज के भंडार को चट करके रख दिया है. इस साल अनाज भंडार घटकर 1.25 करोड़ टन ही रह जाएगा. स्पष्ट है कि सरकार ने सूखे की भरपाई इसी भंडार से की है. इससे भी बढ़कर बात यह है कि अब सरकार भी मानने लगी है कि इस साल अनाज का उत्पादन 14.41 करोड़ टन होगा जो 15 करोड़ टन के लक्ष्य से 64 लाख टन कम है. अभी तक वह लगातार कहती रही है कि 15 करोड़ टन अनाज पैदा होगा पर जनवरी में उसने कमी की बात भी स्वीकार की. ऐसे में निकट भविष्य में भंडार बढ़ने की संभावना नहीं लगती. अनाज भंडार कम होने के बहुत से गंभीर परिणाम निकलते हैं. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये होने वाली खाद्यान्न बिक्री से मुद्रास्फीति पर अंकुश लगा रहता है.

चार्ट: बी.के. शर्मा

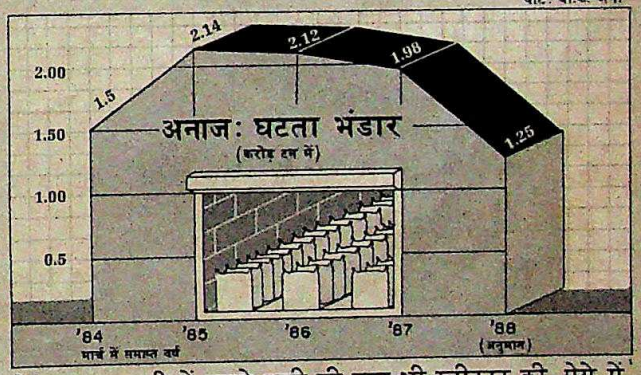

सूत्रधार कौन रहे

सरकारी विभागों में आपसी नोक-झोंक तो चलती रहती है पर इस बार मामला काफी आगे बढ़ गया. इस बार भिड़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग और उद्योग मंत्रालय. मसला है: इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विभिन्न प्रकारों से संबंधित फैसले कौन करे. इलेक्ट्रॉनिक विभाग यह अधिकार चाहता है जबकि उद्योग मंत्रालय यह अधिकार छोड़ना नहीं चाहता. विवाद की वजह यह है कि इलेक्ट्रानिक्स उद्योग का वास्ता कई सरकारी विभागों से पड़ता है जैसे स्वास्थ्य संबंधी परीक्षणों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उद्योग मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में आते हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग इस स्थिति को बदलना चाहता है. वह सार्वजनिक क्षेत्र की सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों को अपने नियंत्रण में लेना चाहता है. इससे और विवाद उठ सकते हैं और तय है कि अभी और गुल खिलेंगे.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बजट निर्माण

एक कष्टसाध्य प्रक्रिया

सालाना आम बजट की विस्तृत तैयारी का विहंगावलोकन

दिल्ली की इस लाल हवेली पर डाला गया घेरा अब उठाया जा चुका है. घेरे के दौरान लिखे और छापे गए दस्तावेज़ यहां से रवाना किए जा चुके हैं. और इस काम के लिए वहां चार दिन तक नजरबंद मेहमानी में रखे गए छपाई कर्मचारियों और सरकारी अधिकारियों को भी विदा किया जा चुका है. विशेष सुरक्षा व्यवस्था भी ढीली कर दी गई है. वित्त मंत्रालय के प्रमुख अधिकारियों के पीछे साये की तरह लगे जासूसों का न तो कहीं अता-पता है और न ही अब उनके टेलीफोन पर खुफिया कान चिपके हुए हैं.

यह सब देखने-सुनने में भले ही अजीब लगे लेकिन यह एक ऐसी कवायद है जो हर साल तैयार किए जाने वाले बजट का स्थायी हिस्सा बन चुकी है. बजट पेश किए जाने के बाद जब नए टैक्स लगने की खबरें सुर्खियों में आती हैं और आर्थिक विशेषज्ञ अपने जाने-पहचाने अंदाज में प्रतिक्रियाएं बांटने लगते हैं तब अक्सर यह बात पीछे रह जाती है कि बजट तैयार करने वालों को कैसे-कैसे पापड़ बेलने पड़े होंगे.

ज्यों-ज्यों बजट का दिन पास आता जाता है, तनाव बढ़ता चला जाता है. अफसरशाह रात देर तक जागते हैं और सुरक्षा व्यवस्था लगातार कसती चली जाती है. दो-तीन साल पहले रेलवे बजट की जानकारी वक्त से पहले बाहर चली गई और नतीजा यह हुआ कि एक वरिष्ठ अफसर ने बजट से दूर का ताल्लुक रखने वाले अधिकारियों पर भी जासूस तैनात कर डाले.

बड़े अफसरों के दायरे में भी सतर्कता का बोलबाला रहता है और वे फाइलें देने के लिए खुद सीढ़ियां चढ़ते-उतरते हैं. सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार विमल जालान बताते हैं, "हर चीज को सीलबंद किया जाता है और संबंधित अधिकारी अपने हाथों से फाइलें संबंधित व्यक्ति को थमाते हैं." यह तो रही अंतिम दिनों की बात, लेकिन कवायद का सिलसिला महीनों पहले शुरू हो जाता है.

जुलाई-अगस्त: शुरुआत होती है इस बात से कि आने वाले साल में कितना खर्च किया जाना है. यहां मामला किसी परिवार से ठीक उलट होता है. पहले तय यह किया जाता है कि सरकार कितना खर्च करे और फिर यह अनुमान लगाया जाता है कि पैसा आएगा कहां से?

खर्च के दो हिस्से रहते हैं—योजना निवेश और गैर-योजना खर्च. योजना आयोग का सचिव पहले पक्ष की देखरेख करता है और वित्त मंत्रालय दूसरे का समन्वय करता है.

सितंबर-अक्तूबर: बैठकों का सिलसिला शुरू होता है जिनमें मंत्रालयों के सचिव और सार्वजनिक उद्यमों के अफसरान किसी मंदिर की तरह नार्थ-ब्लाक की अर्चना परिक्रमा करते हैं. इसके साथ-साथ राजस्व की ताजा और भावी हालत का आकलन करके अगले साल के आंकड़ों के अनुमान तैयार किए जाते हैं. टैक्स लगाने की बात तो बाद में आती है.

नवंबर: सरकार को इस बात का कच्चा-पक्का अंदाजा रहता है कि अगले साल कितना पैसा इकट्ठा किया जा सकता है. बात यहीं से शुरू होती है और इसके साथ ही वित्त मंत्रालय हरकत में आ जाता है. जब दूसरे विभाग अपनी-अपनी मांगें पेश कर रहे होते हैं उस समय वित्त सचिव सिर्फ सुनता रहता है.

मांगों के अंबार को देखते हुए खर्च विभाग के सचिव को तलवार उठानी पड़ती है और इसे वह गैर-योजना मदों पर बेरहमी से चलाता है. इस फैसले को बदलवाने के लिए मंत्री अक्सर प्रधानमंत्री के दरबार तक जा पहुंचते हैं.

दिसंबर: आखिरकार वित्त मंत्रालय दूसरे मंत्रालयों को दो टूक शब्दों में बता देता है कि उन्हें इतने पैसे में गुजारा करना है. इससे

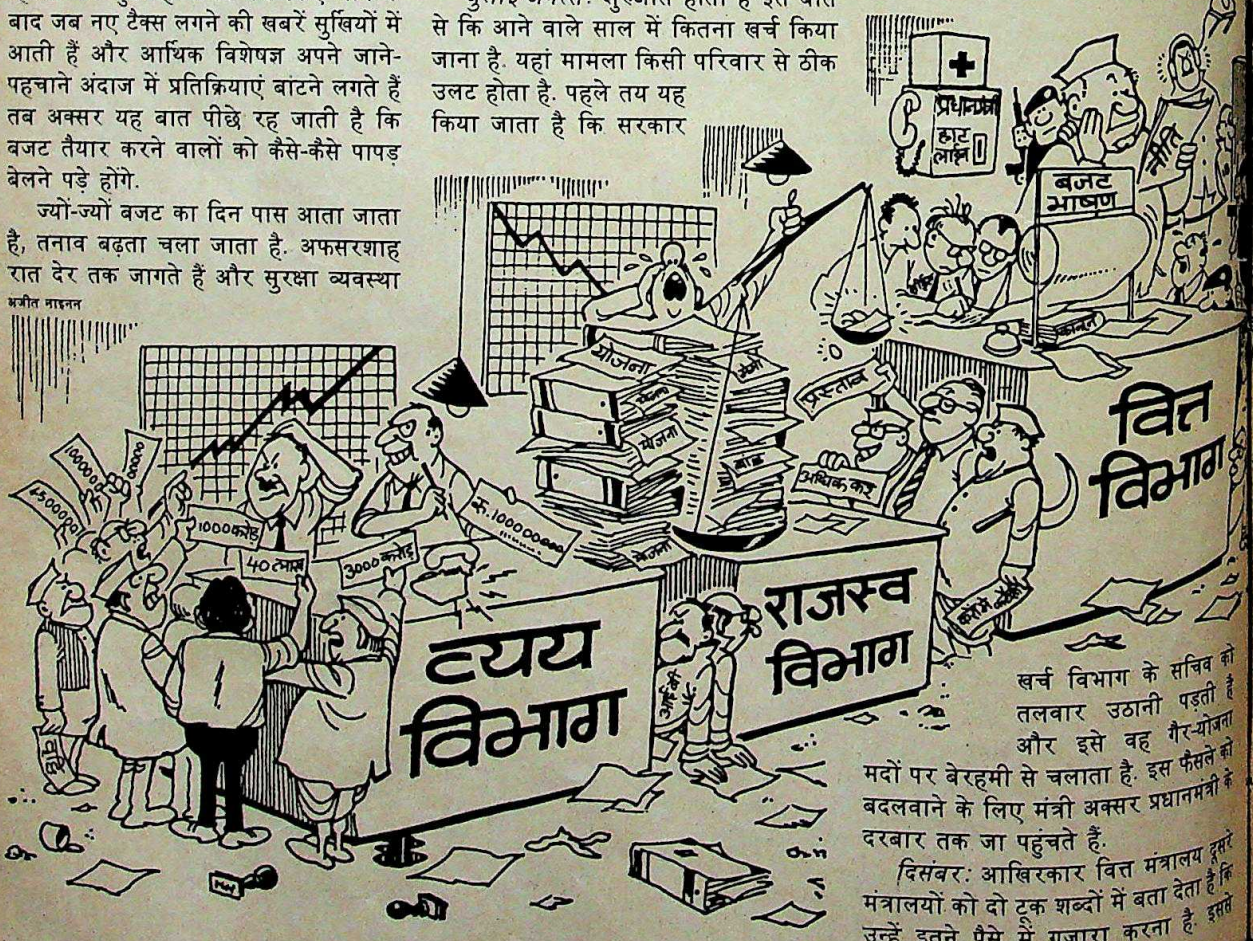

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आगे कुछ नहीं मिलने वाला.

इसके बाद बारी आती है बाहर से आने वाली मांगों की जिसके लिए जमकर लॉबिइंग होती है. सांसदों और औद्योगिक संघों की ओर से सलाहों और मांगों के पुलिंदे पेश किए जाते हैं. एक अधिकारी बताते हैं कि दिवंगत लक्ष्मीकांत झा हर बार कम-से-कम 500 सुझाव भेजा करते थे. इस बार संस्थाओं की ओर से 1000 से अधिक और निजी स्तर पर 3000 से अधिक सुझाव आए. एक अधिकारी का मुंह बनाते हुए कहना था, "अब तो यह हाल है कि लिफाफे पर छपा नाम पढ़कर ही पता चल जाता है कि अंदर क्या सुझाव होगा."

पर इसके बावजूद दावा किया जाता है कि सलाहों पर गंभीरता से ध्यान दिया जाता है.

जनवरी: अब मंच पर वित्तमंत्री का प्रवेश होता है. अब तक वह दूर से ही किसी आर्केस्ट्रा के संचालन की तरह इशारे देकर घाटे की सीमा, दिए जाने वाले दिए जा सकने वाली रियायतों और नए टैक्सों से बटोरी जा सकने वाली राशि के बारे में निर्देश देते आए थे. पर अब वे बजट पर अपनी निजी पहचान का ठप्पा लगाने का काम करते हैं. पूर्व वित्तमंत्री प्रणव मुकर्जी कहते हैं, "हर वित्तमंत्री की अपनी वरीयताएं होती हैं लेकिन पंचवर्षीय योजना के दायरे में रहते हुए उसे इस सब पर प्रधानमंत्री की सहमति की मुहर लगवाना जरूरी होता है."

सक्रियता के इस नए दौर में वित्तमंत्री बजट के बारे में अर्थशास्त्रियों, व्यापारियों, किसानों और पत्रकारों की सलाहें सुनते हैं. उदाहरण के लिए नारायणदत्त तिवारी ने अर्थशास्त्रियों और योजना आयोग के सदस्यों को अलग-अलग बुलाकर उनसे सलाह-मशविरा किया. यह वही दौर होता है जब वित्तमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच बैठकों के सिलसिले की शुरुआत होती है.

यह दरअसल बैठकों का महीना होता है जिनमें वित्तमंत्री अपने दूसरे सहयोगी मंत्रियों, राजस्व और खर्च सचिवों, प्रधान आर्थिक सलाहकार और अतिरिक्त सचिव (बजट) जैसे वरिष्ठ लोगों के साथ हफ्तों बातचीत चलाते हैं. इन बैठकों में कभी-कभार प्रधानमंत्री कार्यालय का कोई प्रतिनिधि भी शामिल हो जाता है. यकीनन इस दौरान लोगों को काफी देर तक काम करना पड़ता है. इन बजट बैठकों में विश्वनाथ प्रताप सिंह स्वयं मौजूद रहा करते थे जबकि तिवारी महीने भर में कुछ बार ही इनकी अध्यक्षता करते हैं.

इन बैठकों में कसरत का मुख्य केंद्र आंकड़े ही रहते हैं. योजना निवेश और गैरयोजना खर्च को जोड़कर देखा जाता है कि कितना पैसा खर्च होना है. रिजर्व बैंक गवर्नर के आंकड़ों में से यह खबर ली जाती है कि बैंकों के पास कितना पैसा है और खर्चों के लिए कुल कितना पैसा उपलब्ध है. बस यहीं से टैक्स प्रस्ताव सिर उठाना शुरू कर देते हैं. टैक्सों का हिसाब-किताब करने की जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय के दो विभागों की रहती है—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड तथा केंद्रीय उत्पादन शुल्क और राजस्व बोर्ड. प्रत्यक्ष करों के मामले में बोर्ड के पास अब ऐसी कंप्यूटर व्यवस्था है जिससे प्रस्तावित करों से होने वाली संभावित आय और करदाता पर इनके प्रभाव का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है.

फरवरी: 10 तारीख आने से पहले ही टैक्स प्रस्तावों को अंतिम रूप दे दिया जाता है ताकि मसविदा तैयार करने वाले लोगों को कानूनी सोच-विचार के लिए कम-से-कम एक सप्ताह मिल सके. महीने के आरंभिक दौर में ही खर्च विवरण संबंधी दस्तावेज तैयार करके छपाई के लिए जारी कर दिए जाते हैं.

और अब समय आता है वित्तमंत्री का बजट भाषण तैयार करने का जिसे प्रधान आर्थिक सलाहकार के निर्देशन में चार सचिवों की समिति कागज पर उतारती है. तय है कि इसमें कई बार फेरबदल भी किए जाते हैं. पिछली बार बजट पेश करने से पहले राजीव ने रात 2 बजे तक बैठकर इस भाषण को अंतिम रूप दिया था.

इस साल भी उन्होंने अब तक तिवारी द्वारा तैयार कराए गए आंकड़ों को देख लिया होगा. एक अधिकारी का कहना था, "राजीव इन आंकड़ों को अपने निजी कैलकुलेटर पर भी चेक करते हैं." वैसे उनके परिवार में यह कोई नई परंपरा नहीं है. उनकी मां भी अपने हर भाषण के एक-एक शब्द को गौर से देखा करती थीं.

इस दौरान बजट लिखने वाले अधिकारियों को प्रेस सूचना कार्यालय के लोगों और छपाई कर्मचारियों के साथ छापेखाने में 'नजरबंद' कर दिया जाता है. यह 'नजरबंदी' बजट भाषण पढ़े जाने के साथ खत्म होती है. और इसके साथ ही साये की तरह अफसरों का पीछा करने वाले और उनके टेलीफोनों को गुपचुप सुनने वाले जासूस भी चैन की सांस लेते हुए बोरिया-बिस्तर लपेट लेते हैं—अगले बजट तक. —पलकुन्नथु जी.मथाई

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

बिकने की तैयारी

आंध्र स्कूटर्स भी निजी क्षेत्र को

आर के. मूर्ति

राहुल बजाज

स्कूटर्स इंडिया लि. में मजदूरों की संख्या आधी कर देने के बजाज के प्रस्ताव के कारण सरकारी इकाइयों के मजदूर संघों ने कंपनी को बेचे जाने का विरोध किया है

लखनऊ की सरकारी कंपनी स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड बिकने को तैयार है. अब तक यह 125 करोड़ रु. का घाटा उठा चुकी है. मजदूरों के विरोध के बावजूद केंद्र सरकार इसे देश की सबसे बड़ी दुपहिया वाहन कंपनी बजाज ऑटो को 17 करोड़ रुपए में बेचने जा रही है. उम्मीद है इसी महीने सौदा हो जाएगा.

उधर आंध्र प्रदेश की सरकारी आंध्र स्कूटर्स लिमिटेड का प्रबंध भी निजी क्षेत्र के हाथों सौंपने की तैयारी चल रही है. इस सिलसिले में कानपुर की एलएमएल (पूर्व नाम लोहिया मशीन्स) और एस्कॉर्ट्स से बातचीत चल रही है. वेस्पा नाम से स्कूटर बनाने वाली इटली की पियागियो कंपनी से बातचीत की जा रही है. एलएमएल और आंध्र स्कूटर्स दोनों ने ही इससे गठबंधन किया है. बातचीत जल्दी ही खत्म होगी. और प्रबंध का करार चाहे एलएमएल से हो या एस्कॉर्ट्स से, आंध्र स्कूटर्स हैदराबाद के पास स्थित अपने कारखाने से वेस्पा के नए मॉडल के स्कूटर और मोपेड का निर्माण शुरू कर देगी. लेकिन एस्कॉर्ट्स के संयुक्त प्रबंध निदेशक अनिल नंदा कहते हैं, "हम लोगों ने संयुक्त क्षेत्र में कंपनी लगाने का अभी पक्का तय नहीं किया है."

इन सबका विरोध भी कम नहीं हो रहा है. स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड वाले मामले पर मजदूरों में बहुत गुस्सा है क्योंकि बजाज यहां के 3225 मजदूरों की फौज को 1500 तक करना चाहते हैं. कंपनी को बेचे जाने के विरोध में सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों के कर्मचारी संगठन 14 मार्च से तीन दिनों की हड़ताल और उसके बाद राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी दे रहे हैं. लेकिन लगता नहीं कि सरकार पर इन चीजों का असर होगा.

कंपनी ने इस साल एक भी विजय स्कूटर (विजय) नहीं बनाया है. तिपहिया गाड़ियों का धंधा अभी भी मुनाफे में चल रहा है फिर भी इसने बहुत कम गाड़ियां ही इस साल बनाई हैं. सबसे बड़ी बाधा रहा इसका कारखाना ही. सत्तर के दशक के शुरू में सरकार ने लैंब्रेटा स्कूटर बनाने वाली इटली की इन्नोसेंटी कंपनी का पुराना कारखाना यहां मंगा लिया था. दूसरी बाधा: 1.30 लाख वाहन बनाने लायक कर्मचारी नियुक्त करने के बाद भी बहुत थोड़े से स्कूटर बनाने का सरकारी फैसला. लेकिन उम्मीद है राहुल बजाज जल्दी ही सब कुछ बदल देंगे.

आंध्र स्कूटर्स की मुश्किलें भी बहुत कुछ ऐसी ही हैं. 1984 में इसने पियागियो से 100 सीसी के वेस्पा स्कूटर बनाने का करार किया. इस उद्योग के अधिकांश लोगों का मानना है कि तकनीकी रूप से यह काफी अच्छा उत्पादन है पर यह लोगों की पसंद पर नहीं चढ़ सका. इसके नए प्रबंध निदेशक धर्म राव एस्कॉर्ट्स और एलएमएल में काम कर चुके थे. कंपनी को पूंजी की जरूरत थी और सरकार तथा वित्तीय संस्थाएं पैसा उपलब्ध कराने के लिए तैयार नहीं थी. इसलिए उन्होंने कंपनी को बचाने के लिए अपने पूर्व मालिकों की ओर रुख किया. इन दोनों कंपनियों से हुई बातचीत में कई सकारात्मक बातें भी हैं. आंध्र स्कूटर्स में 125 सीसी का नया मॉडल ले आ रहा है और इसे एस्कॉर्ट्स और एलएमएल के नेटवर्क से बेचा जाएगा. शायद ये कंपनियां इस नए मॉडल को अपना नाम भी देंगी. आंध्र स्कूटर्स 50 सीसी क्षमता का मोपेड भी लाने वाला है.

दीपक सिंघानिया

अनिल नंदा

एलएमएल और एस्कॉर्ट्स दोनों ही आंध्र स्कूटर्स लि. से करार करना चाहती हैं. अब आंध्र स्कूटर्स का चाहे जिससे करार हो, दुपहिया वाहन बाजार में कड़ी होड़ के संकेत हैं

आंध्र स्कूटर्स से चाहे जिसका करार हो, दुपहिया वाहन बाजार में होड़ के ही संकेत हैं. इस वाहन उद्योग की विकास दर पिछले साल एक फीसदी रह गई. ऐसे में निर्माताओं की संख्या कम होगी. नहीं तो कम ही कंपनियां आगे निकल पाएंगी. —पलकुन्नयु जी. मथाई दिलीप अवस्थी और अमरनाथ के. मेनन के साथ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शेयर बाजार

बढ़ी-चढ़ी आशा

बजट पर निगाहें टिकीं

शेयर बाजार को नारायणदत्त तिवारी से जिस तरह के बजट की उम्मीद है अगर वैसा बजट आया तो उसका भविष्य उज्ज्वल हो सकता है. नहीं तो 1986 के बजट के बाद जैसी गिरावट आई थी, वैसी ही इस बार भी आएगी.

बजट आने की प्रतीक्षा के अंतिम दिनों में बाजार का मूड निश्चित रूप से बेचैनी भरा है. कारोबार काफी घट गया है. जो कारोबार हो रहा है उसमें भी भविष्य के बारे में निश्चितता दिखाई नहीं देती. हर शेयर मूल्य सूचकांक नीचे ही जा रहा है.

अनेक कंपनियों द्वारा अच्छे कारोबार की घोषणा करने के बावजूद ऐसा हो रहा है. अधिकांश लोगों को उम्मीद है कि आने वाले वर्ष में पिछले साल से अधिक पूंजी आएगी और 1986 से निराश हुए निवेशक भी लौटेंगे. लेकिन बाजार के पंडितों की ये उम्मीदें अभी खरी उतरनी बाकी हैं.

चार्ट: बी.के. शर्मा

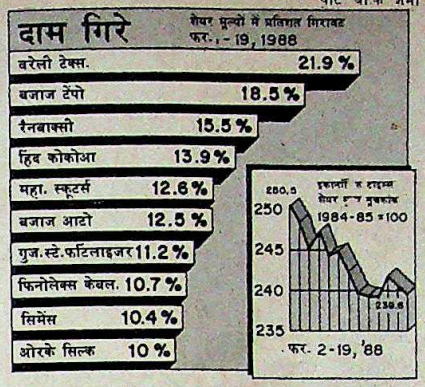

अंदेशा है कि शेयरों की कीमत और गिरेगी. हालांकि गिरावट रोकने की कोशिश होती रही है. दवे कमेटी की सिफारिशों के दूसरे हिस्से को अभी लागू नहीं किया गया है और गिरावट रोकने की कोशिशें बाजार के कारोबार को प्रभावित कर रही हैं. दलालों को अनुशासित करने के लिए लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ उन्होंने पिछले पखवाड़े हड़ताल भी की.

लेकिन अब सारा कुछ बजट पर निर्भर करता है. हर आदमी मानता है कि यह बजट बहुत कठोर होगा. सूखे के कारण सरकार को पैसे की तंगी पड़ गई है और वह टैक्स बढ़ाकर या बाजार से कर्ज उठाकर ही ज्यादा पैसा जुटा सकती है. कर बढ़ने से वित्तीय बाजार का अभी का गणित गड़बड़ा जाएगा और अगर सरकार पैसा उठाती है तो निजी कंपनियों को जाने वाली पूंजी की मात्रा में कमी आएगी. दोनों ही बातों का बाजार पर बुरा असर होगा.

लेकिन बाजार के लोगों को तिवारी से कई उम्मीदें हैं. उन्हें लगता है कि वित्तमंत्री बाजार में आत्मविश्वास भरने और निवेशकों को शेयर बाजार में आकर्षित करने के प्रति सचेत हैं. वे जानते हैं कि निजी क्षेत्र को चलने देने के लिए पूंजी बाजार में दम बना रहने देना चाहिए. अगर कर लगाकर पूंजी बाजार सोख लिया गया या कर्ज उठाने की प्रक्रिया में पूंजी की धारा मोड़ दी गई तो उद्योगों में निवेश की मात्रा कम हो जाएगी.

इन्हीं कारणों से कई जानकार लोगों को उम्मीद है कि निवेश को बढ़ावा देने के लिए बजट में कुछ खास तरह की रियायतें जरूर दी जाएंगी. और तिवारी इन लोगों की उम्मीद पर पानी नहीं फेरेंगे. लेकिन बजट आने से पहले के कुछ हफ्तों में निराशा का भाव ही प्रमुख रहा. यह बात शेयर मूल्य सूचकांकों की गिरावट से भी जाहिर है.

जमा स्टॉक

	1988 ऊंचा	1988 नीचा	1988 बंद 19.2.88	पखवाड़े में स्टॉक की स्थिति
अशोक लेलैंड	36.50	31.00	31.00	1.50 —
एसोसिएटेड सीमेंट	180.00	144.00	157.50	0.50 —
एटलस कोप्को	63.50	43.00	45.00	4.00 —
एशियन पेंट्स	169.00	144.50	151.25	3.75 —
बजाज ऑटो	520.00	401.25	403.75	33.75 —
बड़ौदा रेयॉन	168.00	145.00	155.00	2.50 +
बाटा इंडिया	71.50	60.75	61.75	5.00 —
बेयर	320.00	295.00	300.00	—
भारत फोर्ज	118.00	101.00	111.00	3.00 +
बिरला जूट	44.00	36.50	37.00	1.25 —
ब्लो प्लास्ट	125.00	47.00	49.00	59.75 —
बॉम्बे डाइंग	128.50	94.00	125.00	3.00 —
ब्रुक बांड	87.00	75.00	77.50	1.50 —
ब्रिटानिया इंडिया	109.00	84.00	89.00	2.00 —
सीएट टायर्स	88.00	80.00	86.00	2.00 —
सेंचुरी एंका	1340.00	1080.00	1260.00	—
क्लोराइड इंडिया	80.50	69.00	72.50	1.00 —
सिमुरगिया	74.00	61.00	67.00	5.00 —
कोलगेट	220.00	191.25	195.00	2.50 —
डीसीएम	38.25	29.50	29.50	3.75 —
डनलप	83.00	71.00	74.00	3.50 —
एस्कार्ट्स	44.00	39.00	39.50	2.25 —
फिनोलेक्स केबिल्स	380.00	311.25	318.00	29.50 —
फ्रूड स्पेशिलिटीज	142.00	114.00	117.00	3.00 —
गरवारे नाइलोन	30.00	20.00	23.50	1.50 —
जी.ई. शिपिंग	26.35	20.50	24.75	1.00 +
गुजरात स्टेट फर्टि.	118.00	86.50	103.00	11.00 —
ग्लोसिस इंडिया	104.75	84.50	88.50	3.00 —
हिंदु. एल्यूमिनियम	139.00	116.00	123.00	1.00 +
हिंदुस्तान कोकोआ	215.00	82.50	85.00	5.00 —
हिंदुस्तान लीवर	81.00	66.00	68.50	2.00 —
हिंदुस्तान मोटर्स	25.00	19.70	20.20	1.40 —
हिंदुस्तान डॉर	212.50	145.00	170.00	10.00 +
आई.ई.एल.	43.75	36.50	37.75	1.00 —
इंडियन होटल्स	120.50	100.00	103.00	2.00 —

	1988 ऊंचा	1988 नीचा	1988 बंद 1.2.88	पखवाड़े में स्टॉक की स्थिति
इंडियन आर्गेनिक	23.00	17.50	18.50	0.50 —
इंडियन रेयॉन	58.00	46.00	49.00	1.00 —
इंड्राल	223.75	173.75	176.25	11.25 —
इंगरसॉल-रैंड	335.00	275.00	282.50	7.50 —
आई.टी.सी.	39.75	30.00	33.00	0.50 —
जे.के. सिंथेटिक्स	69.00	49.50	52.50	3.50 —
काइनेटिक इंजी.	185.00	165.00	170.00	—
किर्लोस्कर क्युमिंस	57.50	48.00	51.50	6.00 —
केएसबी पम्प	425.00	360.00	370.00	—
लारसन-टुब्रो	95.50	77.00	81.50	5.50 —
लिप्टन	67.00	52.00	54.50	1.50 —
लोहिया-मशीन्स	13.50	9.00	9.25	0.75 —
महिंद्रा-महिंद्रा	63.00	52.00	56.00	1.00 —
मैक्डोवेल	83.50	73.00	76.00	0.50 —
मोटर इंडस्ट्रीज	587.50	490.00	525.00	5.00 +
मुकुंद आयरन	85.00	72.50	76.00	2.50 —
नेशनल आर्गेनिक	525.00	425.00	445.00	5.00 —
निरलॉन	8.75	5.00	6.50	—
ओरके सिल्क मिल्स	30.00	20.50	22.50	1.00 —
पेइको इलेक्ट्रॉनिक्स	33.75	26.00	27.50	—
ओसवाल एग्रो	134.50	95.50	95.50	19.00 —
ओटिस एलिवेटर	215.00	190.00	197.50	10.00 —
प्रीमियर ऑटो	31.00	24.50	27.00	0.50 +
रैनबेक्सी	102.50	76.00	76.00	14.00 —
रेमंड	96.00	44.00	47.00	1.00 —
शॉ वैलेस	132.00	57.00	59.00	55.00 —
रिलायंस इंडस्ट्रीज	117.00	95.00	96.00	3.00 —
रिचर्डसन हिंद	305.00	260.00	272.50	12.50 —
श्रीराम फाइबर्स	42.75	32.50	35.00	1.00 +
एसकेएफ बियरिंग	1315.00	1058.00	1200.00	20.00 —
सीमेन्स इंडिया	80.00	68.00	69.00	6.00 —
स्पिक	37.00	28.50	31.25	1.25 —
टाटा स्टील	685.00	578.75	600.00	13.75 —
टेल्को	400.00	340.00	360.00	2.50 —
विम्को	24.00	19.00	19.50	1.25 —

भारतीय रुपए का मूल्य

देश	मुद्रा	इकाई	बिक्री मूल्य (रुपए में)	खरीद मूल्य (रुपए में)
आस्ट्रेलिया	डालर	1	9.4309	9.3318
आस्ट्रिया	शिलिंग	1	1.0970	1.0852
बहरीन	दीनार	1	34.7810	34.7138
बांग्लादेश	टका	100	42.2312	42.1800
कनाडा	डालर	1	10.3715	10.2716
डेनमार्क	क्रोनर	1	2.0132	1.9919
मिस्र	पौंड	1	9.3672	9.3001
फ्रांस	फ्रैंक	1	2.3148	2.2558
हांगकांग	डालर	1	1.6914	1.6745
इंडोनेशिया	रुपिया	100	0.0790	0.0780
ईरान	रियाल	100	19.1532	19.1493
इटली	लीरा	100	1.0436	1.0004
जापान	येन	100	10.20	9.95
केन्या	शिलिंग	1	0.7683	0.7310
कुवैत	दीनार	1	47.3613	47.2710
मलेशिया	डालर	1	5.0967	5.0386
मारीशस	रुपया	1	1.0360	0.9910
नेपाल	रुपया	1	0.6218	0.5810
हालैंड	गिल्डर	1	6.8548	6.7836
पाकिस्तान	रुपया	1	0.7511	0.7092
सिंगापुर	डालर	1	6.5368	6.4579
स्पेन	पेसो	1	0.1142	0.1009
श्रीलंका	रुपया	1	0.4261	0.4100
स्वीडन	क्रोनर	1	2.1662	2.1430
स्विट्जरलैंड	स्विस फ्रैंक	1	9.3472	9.2484
तंजानिया	शिलिंग	1	0.1530	0.1490
थाईलैंड	बहत्त	100	51.8128	50.0000
ब्रिटेन	पौंड	1	22.8750	22.7425
सं. राज्य अमेरिका	डालर	1	13.1750	13.0450
सं. अरब अमीरात	दिरहाम	1	3.5732	3.5019
सोवियत संघ	रूबल	1	21.6512	21.6010
पश्चिम जर्मनी	जर्मन मार्क	1	7.8186	7.6219

स्रोत—बैंक ऑफ टोक्यो, नई दिल्ली, 19.2.88

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सभी फोटो: भवान सिंह

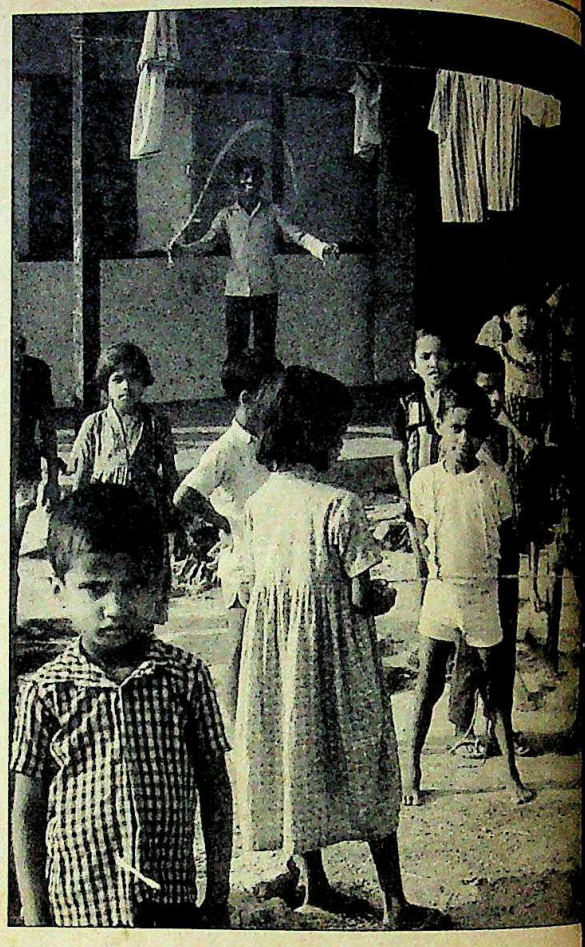

नेल्ली

हादसे से उपजी हार्दिकता

नेल्ली में 18 फरवरी 1983 को हुई खूंरेजी की दहशत और उसके चिन्ह आज भी देखे जा सकते हैं. तब 2000 से ज्यादा क्षत-विक्षत शरीर इधर-उधर छितराए थे और ललचाए गिद्ध उन पर मंडरा रहे थे. असम के इस अनजान गांव की सबसे दहशतनाक यादगार तो उन कुछ घंटों में हुई मासूम बच्चों की नृशंस हत्या की है.

उस कहर भरी शाम को गांव के कुछ ही बच्चे बच पाए थे. सीआरपीएफ का एक गश्ती दल सैकड़ों क्षत-विक्षत लाशों के बीच जीवन की संभावना ढूंढ़ रहा था कि एक जगह उन्हें मामूली हलचल देखकर रुक जाना पड़ा. वह अर्द्धमृत अवस्था में पड़ा एक साल का बच्चा था. बाद में पता चला कि उसका नाम नजरुल इस्लाम है. यह बच्चा अपने परिवार के 24 सदस्यों में से अकेला ही बच पाया था.

नेल्ली, 18 फरवरी 1988: पड़ोस के एक कस्बे होजई में पिछले पखवाड़े एक झोंपड़ी में बच्चों का शोर गूंज रहा था. नए कपड़ों में सजा-संवरा एक बच्चा झोंपड़ी में दूसरे बच्चों से छोटे-छोटे उपहार ले रहा था. उसकी खुशी जायज भी थी. वह पहली कक्षा में 92 प्रतिशत अंकों के साथ पास हुआ था और उसी खुशी में इस पार्टी का आयोजन किया गया था. उस बच्चे का नाम था— नजरुल इस्लाम.

एक मायने में पिछले पखवाड़े का यह आयोजन सिर्फ नजरुल इस्लाम के लिए ही नहीं बल्कि नेल्ली के सभी जीवित बचे अनाथ बच्चों के लिए था. पुनर्वास के लिए बनाए गए एक अनोखे और सफल कार्यक्रम के तहत इन बच्चों के दिमाग से पांच साल पहले के उस दुःस्वप्न की यादें आहिस्ता-आहिस्ता मिटा दी गई हैं. इन बच्चों के पुनर्वास के लिए विशेष रूप से बसाए गए एक नए गांव में आज

नेल्ली: 18 फरवरी 1983

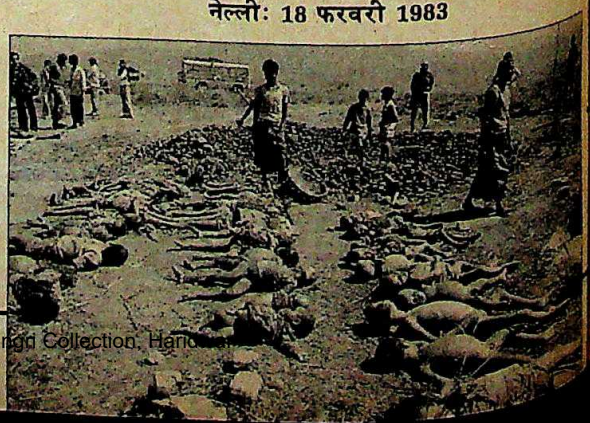

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hard

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

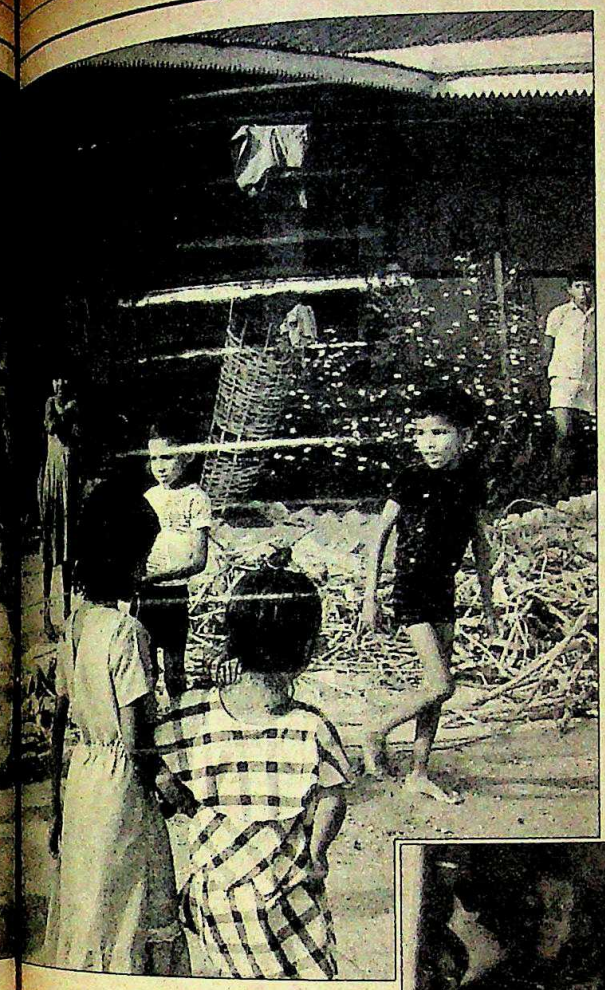

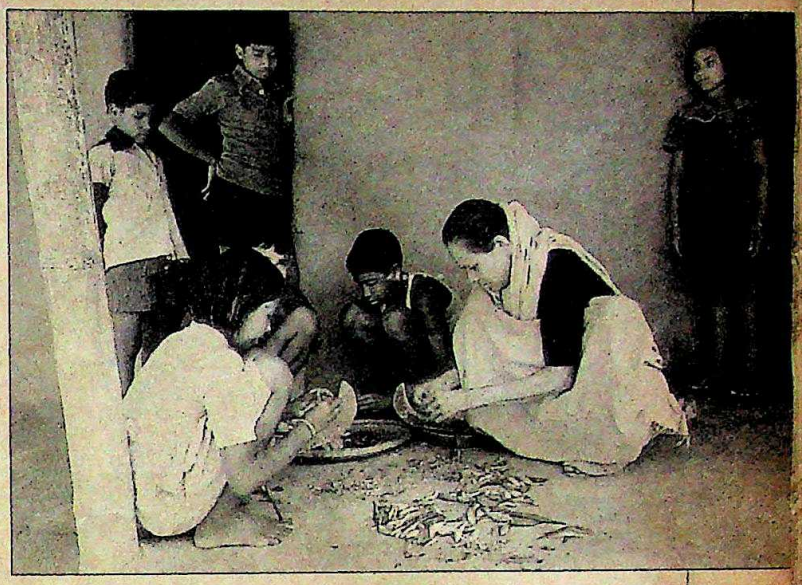

पुनर्वास के एक अनोखे और सफल कार्यक्रम के तहत नेल्ली के जीवित बचे अनाथ बच्चों के दिमाग से पांच साल पहले के दुःस्वप्न की यादें आहिस्ता-आहिस्ता मिटा दी गई हैं और अब वे लगभग सामान्य जीवन जी रहे हैं

(ऊपर बाएं से) होजई में प्रातःकालीन प्रार्थना, खेलकूद में रमे, फिर काम में भी लीन, और (दाएं) नजरुलः अनूठा तालमेल

नजरुल इस्लाम नेल्ली के दूसरे 80 अनाथ बच्चों के साथ लगभग स्वाभाविक जीवन बिता रहा है.

'भारत में एसओएस बच्चों का गांव' परियोजना के तहत बसाए गए इस गांव में असम आंदोलन के छह सालों के दौरान जातीय और सांप्रदायिक दंगों के कारण अनाथ हुए 312 बच्चे रहते हैं. (एसओएस का अर्थ है— 'सेव अवर सोल' यानी हमारी रक्षा करो). इस एसओएस गांव में हिंदू बच्चे भी हैं और मुसलमान बच्चे भी, पर नेल्ली के बच्चों के लिए धर्म कोई भेदभाव की चीज नहीं है. पांच साल पहले के कुछ घंटों के आतंक ने उन्हें पारिवारिक बंधन में भी मजबूत बंधन में बांध दिया है.

होजई कस्बे की 8 एकड़ जमीन में 22 झोंपड़ियां हैं और हर झोंपड़ी में उनकी सेवा के लिए एक 'धर्ममाता' है. चार साल पहले जब परियोजना शुरू हुई तो आसपास के गांवों से निस्संतान विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को विशेष रूप से यहां लाया गया और सभी अनाथों को किराए पर लाई गई इन 'माताओं' को सौंप दिया गया. ऐसी हरेक मां के जिम्मे करीब 12 बच्चे दिए गए और उनसे पारिवारिक माहौल बनाने को कहा गया. भिन्न-भिन्न जाति, धर्म और पृष्ठभूमि के अनाथ बच्चों को एक साथ जोड़ पाना सचमुच आसान नहीं था.

लेकिन परियोजना खासकर इसी समस्या को ध्यान में रखकर बनाई गई थी. हरेक 'परिवार' अपना घर बार स्वतंत्र रूप से चलाता है, जरूरत और वित्तीय क्षमता के हिसाब से अपना-अपना खाना पकाता है. केंद्र सरकार हरेक बच्चे के लिए प्रतिमाह 150 रुपए अनुदान देती है और एसओएस इसमें 25 रुपए अपनी तरफ से जोड़ता है. इतनी कम रकम खर्च किए जाने के बाद भी बच्चे भले-चंगे दिखते हैं. वे साफ कपड़े पहनते हैं, साफ-सुथरे घरों में रहते हैं और माताएं उनके लिए खिलौने और शृंगार की वस्तुएं खरीदने के लिए पैसा भी बचा लेती हैं.

यहां अनाथालयों जैसा बोझिल वातावरण एक भी झोंपड़ी में देखने को नहीं मिलता. किसी आम घर की तरह ही इन झोपड़ियों की लिपी-पुती दीवारों पर नेताजी सुभाषचंद्र बोस से लेकर श्रीदेवी तक की तस्वीरें टंगी हैं. बच्चे घर के दैनिक कामों में हाथ बंटाते हैं और माताएं उनकी पढ़ाई और कठिन कामों में उनकी सहायता करती हैं.

हरेक बच्चे के प्रति इन धर्ममाताओं का कितना लगाव है इसे बिना देखे विश्वास नहीं किया जा सकता. नेल्ली नरसंहार में अनाथ हुए 9 वर्षीय हरकांत बोरा को पिछली गर्मियों में उल्टियां आने लगीं.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बीमारी खतरनाक नहीं थी और गांव की नर्स ने कुछ दवाइयां भी दीं. लेकिन उसकी मां खुदेजा बेगम बहुत घबराई हुई थीं और उसे अस्पताल ले जाने पर जोर दे रही थी. अस्पताल में वे बच्चे के पास से हटने के लिए कतई तैयार नहीं हुईं. बच्चे के प्रति उनके इस लगाव को देखकर डॉक्टर भी चकित रह गए.

इसका एक कारण तो यह भी है कि बच्चों की तरह ही इन धर्ममाताओं का जीवन भी जल्दी आए विधवापन या परित्यक्त जीवन से कष्टमय रहा है. नजरुल इस्लाम की मां 35 वर्षीय रुजेफा सुल्ताना कहती हैं, "जब खाविंद मरे तो मुझे लगा कि मेरा सब कुछ लुट चुका है. लेकिन यहां बच्चे को पाकर मेरी हताशा दूर हो गई."

यही बात अनाथ बच्चों पर भी लागू होती है. पांच सालों बाद नेल्ली की खौफनाक यादें अब छंटती जा रही हैं. नजरुल इस्लाम ने नरसंहार की बात दूसरों से सुनी है पर उसे कुछ भी याद नहीं. उसकी एकमात्र चिंता पढ़ाई ठीक से करने की है. लेकिन ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें उस दिन की छोटी-मोटी घटनाएं याद हैं. मसलन 14 वर्षीय जहांआरा बेगम को याद है कि कैसे उसके पिता का सिर अलग कर दिया गया था. उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई थीं और कुछ ही दिनों में चल बसीं. आतंकित रिश्तेदारों ने इस मासूम को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था. लेकिन होजई में धर्ममाता की देखरेख में उसमें एक नया आत्मविश्वास जाग उठा है. वह कहती है कि वह बहुत आगे जाएगी. उसे राज्य से स्कॉलरशिप भी मिलती है. एसओएस गांव का वातावरण उस घटना की यादें भुलाने में उसके लिए बहुत हद तक सहायक रहा है. वह पूरे विश्वास से कहती है, "अब नेल्ली जैसी घटना फिर कभी नहीं होगी."

घृणा और आतंक की दलदल से यहां शांति और सांप्रदायिक भाईचारा उभरा है. शायद होजई ही ऐसा स्वर्ग है जहां नेल्ली के बच्चों को शांति मिली है. न केवल उनका जीवन बदला बल्कि उनके दिलों के जख्म भी भर गए हैं

दस वर्षीय शोहराब अली को नेल्ली की घटनाओं का कुछ भी याद नहीं पर उसके शरीर पर पड़े निशान खुद ही बोलते हैं. उसके सिर, चेहरे और हाथ पर गहरे निशान हैं जो 'दाय' (एक तरह का कुल्हाड़ा) की मार से हुए हैं. लेकिन उसकी कमीज पर छपे शब्द ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं: "बच्चों को शांति चाहिए." वह एक अच्छा चित्रकार बनना चाहता है और हाल ही में उसे चित्रकारी में बहुत अच्छे नंबर मिले हैं.

एक बार होजई में आए कुछ लोगों ने जानना चाहा कि कौन बच्चा हिंदू है और कौन मुसलमान. उनके जाने के बाद गांव के निदेशक, 33 वर्षीय अजीमुद्दीन चौधरी से बच्चों ने अपनी नाराजगी जाहिर की. चौधरी कहते हैं कि वह उनके जीवन का सबसे संतोषजनक क्षण था.

होजई में सांप्रदायिक सद्भाव का एक अनोखा नमूना पिछले साल की एक घटना में भी दिखता है. नेल्ली का एक अनाथ 15 वर्षीय मुजीबुर्रहमान अपनी 'बहन' सुशीला देवी से छेड़छाड़ करने वाले एक मोटर मेकेनिक से उलझ पड़ा. होजई कस्बे के लोगों को लगा कि किसी मुसलमान की हिंदू बहन कैसे हो सकती है. एसओएस गांव में सुशीला मुजीबुर के साथ एक ही घर में रहती है. चौधरी गर्व से कहते हैं, "सिर्फ यहीं के बच्चे समझ सकते हैं कि ऐसा लगाव कितनी आसानी से पैदा हो जाता है."

11 वर्षीय मुहम्मद तैजूल इस्लाम को पांच साल पहले का वह दिन याद है जब हथियारों से लैस भीड़ ने गांव पर धावा बोल दिया था. उसने अपने मां-बाप को टुकड़े-टुकड़े होते देखा. उसके परिवार के सभी 12 सदस्य कुछ मिनटों में मार दिए गए. लेकिन आज उसके विचार उम्र की तुलना में कहीं समझदारी भरे हैं. "मुझे अब एक नया परिवार मिल गया है. मुझे अतीत भुला देना होगा."

होजई में 16 वर्षीय मुहम्मद रफीक इस्लाम नेल्ली के अनाथों में सबसे बड़ा है. वह एसओएस गांव में एनसीसी की इकाई का कमांडर है. वह कहता है, "मैं सामाजिक कार्यकर्ता बनूंगा...मैं अंधे समाज को दिखा देना चाहता हूं कि जीवन लेकर नहीं बल्कि जीवन दान देकर हम क्या कुछ कर सकते हैं."

यह सब होजई का करिश्मा है. घृणा और आतंक की दलदल से ही यहां शांति और सांप्रदायिक भाईचारा उभर आया है. यहां से 40 किमी दूर जीवन सामान्य हो गया है. महिलाएं झरनों में मछली मारती हैं और बच्चे छोटे-छोटे पत्थरों से खेलते हैं. मिट्टी और छप्पर के घर फिर से दुरुस्त कर लिए गए हैं. उस नरसंहार के बाद अब इस इलाके में सांप्रदायिक तनाव की एक भी घटना नहीं हुई. इस नए सांप्रदायिक सद्भाव में योगदान शायद होजई का ही है. शायद होजई ही अकेला ऐसा स्वर्ग है जहां नेल्ली के बच्चों को शांति मिली है. होजई ने सिर्फ उनका जीवन ही नहीं बदला, उनके दिलों पर लगे जख्म भी भर दिए हैं.

—रमेश मेनन, नेल्ली से

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सकाल

मिल्कियत का झगड़ा

शरद पवार के भाई को संस्थापकों के वारिसों की चुनौती

आखिरकार जब फैसला हुआ तो दोनों पक्ष हतप्रभ रह गए कि जीत हुई किसकी. झगड़ा पुणे के सबसे ज्यादा बिकने वाले दैनिक 'सकाल' (प्रसार संख्या लगभग 1.5 लाख) के स्वामित्व का था. एक तरफ लीला पारूलेकर और उनकी मां शांता पारूलेकर थी. तो दूसरी ओर थे कई प्रकार का धंधा करने वाले प्रताप पवार जो इंका नेता शरद पवार के भाई हैं.

1933 में लीला के पिता नानासाहेब पारूलेकर ने इस अखबार की स्थापना की थी. लीला सकाल न्यूज पेपर प्राइवेट लिमिटेड के शेयर स्थानांतरित करने से रोकने में सफल रही थी. उनकी यह कामयाबी ही विवाद का कारण बनी. 13 जनवरी को बंबई हाईकोर्ट के न्यायाधीश शाम वरिआवा ने कहा कि 1984-85 को पवार को बेचे गए शेयर खरीदने के लिए पारूलेकर परिवार को 1 मार्च तक 79.36 लाख रुपए जुटाने होंगे वरना उनकी याचिका खारिज कर दी जाएगी.

लड़ाई का पहला दौर चाहे जैसा रहा हो, इतना तय है कि झगड़ा जल्दी ही खत्म नहीं होने वाला. इस विवाद की जड़ें दरअसल नानासाहेब की वसीयत में हैं जो उन्होंने 1973 में मृत्यु से पहले लिखी थी. उन्होंने कुल 7,332 शेयरों में से 1,170 शेयर लीला को और 560 शांता को दिए थे. बाकी 3,417 शेयर उन्होंने वसीयत लागू करने वालों के लिए रखे. उनके दोस्त डॉ. बानो कोयाजी को 750 शेयर मिले और एक वकील जसवंत मटुभाई के हिस्से 93 शेयर आए. वसीयत लागू करने वालों में लीला ट्रस्ट को भी 1317 शेयर मिले.

मां-बेटी ने सबसे पहले 1975 में 'सकाल' के निदेशकों के खिलाफ साझा तौर पर कई मुकदमे दायर किए थे. कानूनी विवाद तभी से चल रहा है. 27 नवंबर 1984 को 'सकाल' के निदेशक मंडल ने वसीयतनामा लागू करवाने वालों तथा मटुभाई के 3,510 शेयर बेचने का फैसला किया. कंपनी की नियमावली के अनुसार यदि कोई अपने शेयर बेचना चाहे तो बिक्री का प्रस्ताव पहले उसे पारूलेकर परिवार से करना होगा. लीला का कहना है कि इस नियम का पालन नहीं किया गया.

जब कंपनी के लेखा परीक्षकों ने प्रत्येक शेयर की कीमत 2,261 रु. आंकी तो लीला ने इस गणना को चुनौती दे दी कि 1983 में संपत्ति कर के लिए प्रति शेयर की कीमत 400 रु. आंकी गई थी. "दो सालों में शेयरों की कीमत में इतनी बढ़ोतरी कैसे हो सकती है?" लीला ने शेयरों के लिए 79.36 लाख रु. के बजाय 20 लाख रु. जमा करने की पेशकश की. विवाद चलता रहा और सितंबर 1985 को निदेशक मंडल की बैठक हुई तो पारूलेकर परिवार वाकआउट कर गया. बैठक में 2,261 रु. प्रति शेयर के हिसाब से प्रताप पवार समूह को शेयर बेचने की औपचारिक घोषणा कर दी गई. प्रताप को कंपनी का निदेशक बना दिया गया.

प्रताप के नियंत्रण के समय कंपनी के 7.5 लाख रु. के अल्प पूंजी आधार को 100-100 रु. के 17,666 शेयर जारी करके बढ़ाने का फैसला किया गया. लीला ने इसे अनुचित करार दिया. उनका कहना था कि उनका प्रतिद्वंद्वी सिर्फ 17 लाख रु. देकर कंपनी में भारी बहुमत हासिल कर लेगा. पर प्रताप पूंजी निवेश कार्यक्रम का जोरदार समर्थन करते हैं.

इसमें कोई शक नहीं कि प्रताप की अगुआई में 'सकाल' काफी फला-फूला है. दिलचस्प है कि मामले की सुनवाई के दौरान पारूलेकर परिवार को बड़ी संख्या में शेयर देने की पेशकश की गई. इससे कंपनी पर उनकी पहले जैसी पकड़ हो जाती. उन्होंने प्रस्ताव ठुकरा दिया.

प्रताप पवार (बाएं); और अपनी मां के साथ लीला पारूलेकर

पारूलेकर परिवार और प्रताप पवार के बीच यह विवाद अरसे से चला आ रहा है. इसका सुलझना आसान नहीं लगता

लीला अभी 'सकाल' में काम करती हैं और उप-महाप्रबंधक के रूप में सालाना 90,000 रु. पाती हैं. पारूलेकर परिवार जहां प्रकाशन पर कब्जा करने के लिए कमर कसे है, वहीं वह इसके शेयरों की कीमत कम करने की भी ठाने हुए है. उनकी एक रणनीति यह हो सकती है कि वे अदालत में याचिका दायर कर शेयर की कीमत 2261 रु. से घटाकर 458 रु. करने की मांग करें. प्रताप ने 17,666 शेयरों में से प्रत्येक का मोल 100-100 रु. लगाने के बाद वास्तव में 458 रु. ही प्रत्येक शेयर के लिए चुकाए हैं. इतना तय है कि 'सकाल' के कानूनी सीरियल के अभी कई एपीसोड देखने को मिलेंगे.

—सलिल त्रिपाठी, पुणे में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अफगानिस्तान

गृहयुद्ध के आसार

रूसी सेना की वापसी के बाद भी स्थिरता कायम होना मुश्किल

सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव की इस नाटकीय घोषणा से कि 15 मई से अफगानिस्तान से रूसी सेना की वापसी का क्रम शुरू हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में रस्साकशी का नया दौर शुरू हो गया है. लेकिन रूसी सेनाओं के हटने से अफगानिस्तान में नई सरकार के गठन को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल उठ खड़े हुए हैं. पाकिस्तान में पेशावर और आसपास के इलाकों में बसे लाखों शरणार्थियों तथा वहां से अपनी गतिविधियां चलाने वाले कई विद्रोही गुटों की भूमिका इस मामले में यकीनन निर्णायक साबित होगी. शरणार्थियों की मनोदशा और पाकिस्तानी सरकार का रुख जानने के लिए स्वतंत्र पत्रकार ***अरुण चाको*** *ने पिछले पखवाड़े पेशावर की यात्रा की :*

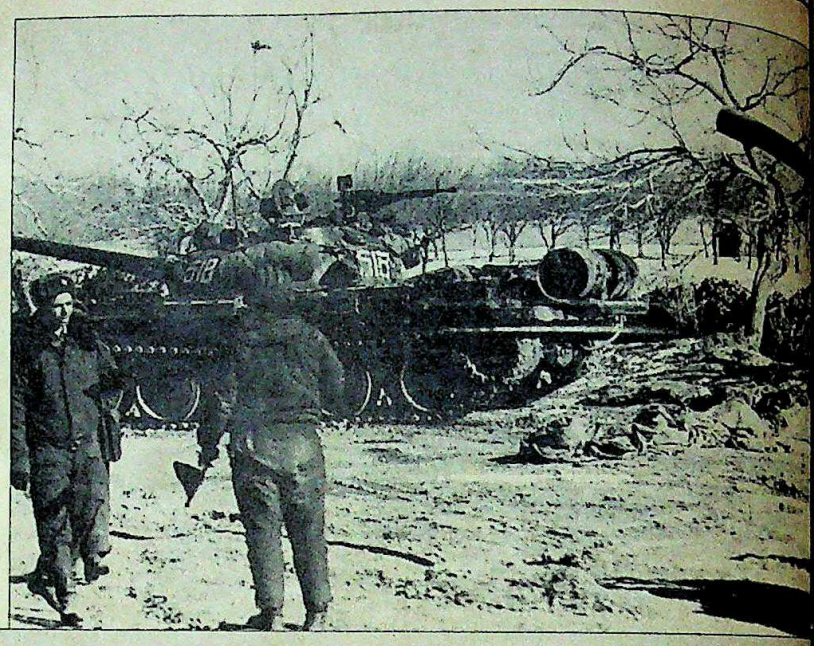

रूसी सेनाओं की वापसी से खूनखराबे की आशंका

इस साल के आखिर तक अफगानिस्तान से सोवियत सेना की वापसी की संभावना की खबर से धूल भरे सीमावर्ती शहर में टिके लाखों शरणार्थियों में सरगर्मियां तेज हो उठी हैं. लेकिन उम्मीद के साथ कड़वी हकीकत भी मुंह बाये खड़ी है. संयुक्त राष्ट्रसंघ के मध्यस्थ डियागो कार्डोवेज की देखरेख में अगले हफ्ते पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच होने वाली बातचीत के बावजूद किसी स्थायी हल की गुंजाइश नजर नहीं आ रही.

असल में समस्या के हल में सबसे बड़ी रुकावट रूसी सेनाओं की वापसी के बाद बनने वाली सरकार के स्वरूप को लेकर है. वाशिंगटन और इस्लामाबाद की सरकारें अपने पहले के रुख के विपरीत अब रूसियों की वापसी से पहले ही इस मसले को तय करने की मांग कर रही हैं. दूसरी तरफ रूसियों ने स्पष्ट कर दिया है कि नई सरकार कैसी होनी चाहिए यह पूरी तरह 'अफगानिस्तान का अंदरूनी मामला' है. उन्होंने वहां मिली-जुली सरकार के गठन में सहायता देने के सुझावों को भी नामंजूर कर दिया है.

ऐसी हालत में अफगानिस्तान की संधि से अपेक्षाकृत बड़ी आग भड़क उठने के अंदेशे को बेबुनियाद नहीं कहा जा सकता. इस्लामाबाद में फिलहाल चल रही अस्वाभाविक कूटनीतिक गतिविधियों ने भी इस आशंका को बलवती ही किया है. राज करने के एकछत्र अधिकार की मांग करने वाले पेशावर स्थित अमेरिकी समर्थक मुजाहिदीन उग्रवादियों के अलावा प्रायः सभी पक्ष पेरिस में रह रहे पूर्व राजा जहीर शाह के नेतृत्व में साझा सरकार बनाने पर सहमत हैं. लेकिन इतना तय है कि किसी भी तरह की संधि में इस मूलभूत तथ्य को दरकिनार नहीं किया जा सकेगा कि अफगान कई गुटों में बंटे हुए हैं और सत्ता के लिए एक दूसरे से लड़ने को तैयार हैं.

पेशावर में ज्यादातर पाकिस्तानी नागरिकों ने इस पहल का स्वागत इस उम्मीद से किया है कि समझौते के कारण पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में शरणार्थियों; हथियारों और हेरोइन की अबाध आमद रुक जाएगी. 1979 में अफगानिस्तान में रूसी सेना की घुसपैठ के बाद से ही यह सिलसिला शुरू हो गया था. शहर के मशहूर बाजार किस्सा खवानी बाजार के एक दुकानदार मुहम्मद शमीम ने कहा, "शहर में वेश्यावृत्ति और नशाखोरी जैसी सामाजिक बुराइयों के साथ ही अपराध दर और हिंसा में बेतरह बढ़ोतरी हो गई है."

बमों के लगातार होते धमाकों से पारस्परिक सौमनस्य में दरारें पड़ गई हैं. इन धमाकों के लिए कौन जिम्मेदार है, लोगों को यह आज भी साफ-साफ मालूम नहीं. यह अफगानी शरणार्थियों की भी करतूत हो सकती है और अफगानिस्तानी खुफिया एजेंसी 'खाद' की भी. कुछ भी हो पर स्थानीय लोग शरणार्थियों की मौजूदगी को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं. और अब वे चाहते हैं कि उन्हें बाहर किया जाए. लेकिन शरणार्थियों की वापसी असंभव-सी लगती है. अगर रूसी वापस चले जाते हैं तो अत्याधुनिक शस्त्रों से लैस विभिन्न गुटों के आपसी झगड़े के कारण अफगानिस्तान को दूसरा लेबनान बनने से रोकना मुश्किल-सा दिखता है. फिर जैसा कि कार्डोवेज ने कहा है, सर्वमान्य अंतरिम सरकार के लिए पाकिस्तान और अमेरिका की शर्त की जिद तो लगता है बनी ही रहेगी. अंतरिम सरकार में छोटी या बड़ी भूमिका निभाने वाले अफगानिस्तान के मुख्य दल आपस में इस कदर बंटे हुए हैं कि भयानक गृहयुद्ध का ही एकमात्र वास्तविक अनुमान लगाया जा सकता है.

पेशावर में शरणार्थियों का प्रतिनिधित्व करने वाला मुजाहिदीनों का सात दलीय गठबंधन बना हुआ है. इनमें चार दल उग्र इस्लामपंथी हैं और तीन उदारवादी हैं. उदारवादी जहीर शाह के नेतृत्व में मिली-जुली अंतरिम सरकार के विरोधी नहीं हैं लेकिन अमेरिका से हथियार पाने वाले मुजाहिदीनों ने निर्वासन झेल रहे राजा को नामंजूर कर दिया है. वे रूसियों से सीधे बातचीत करना चाहते हैं. उधर रूसी मुजा-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हितों को डकैत मानते हैं और वे उनसे कोई बातचीत नहीं करना चाहेंगे.

पाकिस्तान डीपीए को साझा सरकार में एक तिहाई हिस्सा देने और बाकी स्थानों का बंटवारा पेशावर स्थित मुजाहिदीनों और अफगान शरणार्थियों में बराबर-बराबर करने की बात कर रहा है. इसका मतलब यह है कि दो तिहाई स्थानों पर रूढ़िवादियों का नियंत्रण होगा, क्योंकि मुजाहिदीनों का नेतृत्व ही हावी करता है कि कौन शरणार्थी है. जनरल जिया का कहना है, "अफगान मुजाहिदीनों को एक तिहाई हिस्सा क्यों न दिया जाए, बाकी एक तिहाई शरणार्थियों को आंदोलन का नेतृत्व करने वालों को तथा एक तिहाई मौजूदा शासकों को क्यों न मिले."

हालांकि संयुक्त राष्ट्र के मध्यस्थ कार्डोवेज़ पेशावर के विद्रोही नेताओं, अफगानिस्तान में जूझ रहे मुजाहिदीनों और वर्तमान शासकों को अंतरिम सरकार में 30-30 फीसदी हिस्सा देने के समझौते के हिमायती हैं उनकी राय में बाकी 10 फीसदी हिस्सा उन एक्सों के बाहर के गुटों को दिया जाना चाहिए. दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी इन प्रस्तावों पर मतभेद हैं. वहां सेना रूसियों पर राजनैतिक दबाव बनाए रखना चाहती है ताकि उसे प्रचुर मात्रा में सहायता मिलती रहे. लेकिन प्रधानमंत्री जुनेजो और वहां के नागरिक चाहते हैं कि रूसी सेना की वापसी का रास्ता खुले ताकि शरणार्थी जा सकें.

हुमायूं में अफगानिस्तान में ऊंट चाहे जिस करवट बैठे, डीपीए की सरकार और उसके सहयोगियों पर ही सबसे पहले कहर टूटेगा. लेकिन नजीबुल्ला की अगुआई वाली डीपीए भी 'खल्क' और 'परचम' गुटों में बंटी हुई है और ये गुट एक-दूसरे पर हिंसक हमले करते रहे हैं. वयोवृद्ध मौलवी मुहम्मद यूनिस खलिस एक शक्तिशाली विद्रोही गुट के नेता हैं और हाल तक कार्डोवेज़ मिशन से उनका कुछ लेना-देना नहीं था. लेकिन आखिरकार उन्हें पाकिस्तान के दबाव में आकर फरवरी के शुरू में कार्डोवेज़ से मिलना पड़ा. लेकिन कम ही उम्मीद है कि वे गैर-मुजाहिदीनों को सत्ता में साझेदार बनाने को राजी होंगे.

क्योंकि नई सरकार के स्वरूप पर बागी नेताओं में मतभेद हैं

एएफपी

हेज़्बे इस्लामी के मृदुभाषी नेता, पूर्व इंजीनियर 36 वर्षीय गुलबेदिन हिकमतयार भी वैसे ही अक्खड़ हैं. खलिस की तरह ही उन्होंने भी हाल ही में यह बात दुहराई कि अफगानिस्तान के मसले के सिर्फ दो ही पक्ष हैं—मुजाहिदीन और रूस. इसलिए समझौता उन्हीं के बीच हो सकता है.

लेकिन निकट भविष्य में तो वही पक्ष भारी पड़ सकता है जिसके पास हथियारों का बड़ा जमावड़ा है. हिकमतयार के अमेरिका विरोधी रुख के बावजूद हेज़्बे इस्लामी को ही अमेरिकी सहायता का बड़ा हिस्सा मिला है. 1986 के अंत में स्टिंजर मिसाइल उसे ही सबसे पहले मिली थीं. लगता है कि हेज़्बे इस्लामी गठजोड़ के दूसरे सहयोगियों की कीमत पर भी अपना ज्यादा-से-ज्यादा नियंत्रण कायम करना चाहती है. कुछ समय के लिए तो इसने अफगानिस्तान में फसाद खड़े कर दिए और बिना समझे-बूझे स्थानीय नेताओं का सफाया करने लगी. पिछले अगस्त में दक्षिणी अफगानिस्तान में हेज़्बे इस्लामी और अफगानी मुल्ला-मौलवियों द्वारा समर्थित 'हराकत' के बीच झगड़े में सैकड़ों लोगों को प्राणों से हाथ धोने पड़े थे.

मुजाहिदीनों के पेशावर स्थित नेता तो अपेक्षाकृत ऐशो-आराम की जिंदगी बिता रहे हैं लेकिन मुजाहिदीनों के करीब 60 स्वतंत्र गुट अफगानिस्तान में सक्रिय हैं. पिछले आठ बरस से ये मुजाहिदीन अफगानिस्तान के बीहड़ ग्रामीण इलाकों में रूसी सैनिकों से छापामार लड़ाई लड़ रहे हैं.

हो सकता है कि पेशावर स्थित मुजाहिदीन गुटों को मिलने वाले समर्थन का आकलन भी बढ़ा-चढ़ाकर किया जा रहा हो. इसका एक बड़ा कारण तो शुद्ध रूप से आर्थिक ही है. आम शरणार्थियों को राशन और दूसरी सुविधाओं के लिए किसी एक गुट के सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है. इसके साथ ही अफगानिस्तान के भीतर रूसियों के लड़ने वाले कमांडरों को अमेरिकी हथियारों की जरूरत पड़ती है और हथियार पेशावर के गुट ही उन तक पहुंचा सकते हैं.

इन सबके अतिरिक्त सबसे पेचीदा सवाल नशीली दवाओं के कमाऊ व्यापार का है. यह जगजाहिर है कि छापामार दलों के कई मुखिया इसमें खूब चांदी काट रहे हैं. संपत्ति के इस स्रोत की रक्षा के लिए उनमें घमासान युद्ध प्रायः तय ही है.

रूसियों की वापसी अमेरिका के लिए भी समस्याएं खड़ी कर देगी. पाकिस्तान में बैठकर अमेरिका रूस पर दबाव ही नहीं बनाए रखता है बल्कि बलूचिस्तान बंदरगाह के खाड़ी के देशों पर भी अपनी प्रभुता कायम रखता है. इसलिए वापसी के सवाल पर अमेरिकी दुविधा में फंस गए हैं. थोड़े ही समय पहले अमेरिका ने साझा सरकार के प्रस्ताव को नकार दिया था. असल में अमेरिका किसी रूढ़िवादी गुट को चाहता है. अफगानिस्तान में अपनी पकड़ कायम करने के लिए वह उसे पर अपना नियंत्रण रख सकता है और उसे हथियार भी देते रह सकता है.

ऐसी पेचीदा हालत में जबकि महाशक्तियों, पाकिस्तान, संयुक्त राष्ट्रसंघ, काबुल की वर्तमान सरकार, दुविधाग्रस्त पूर्व राजा, विभाजित छापामार गुटों और लाखों शरणार्थियों के अलग-अलग हित तथा मंसूबे हों, हरेक को संतुष्ट कर सकने वाला कोई करार हो सकेगा इसकी उम्मीद न के बराबर दिखती है. सबकी रजामंदी की साझा सरकार बनाना निहायत ही मुश्किल काम है. और उसे बनाए रखना तो उससे भी मुश्किल.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शहंशाह

विवाद का फल मीठा

तमाम आशंकाओं के बावजूद अमिताभ की धमाकेदार वापसी

पहले धमकी भरे पत्रों का सिलसिला चला, "अगर तुमने 'शहंशाह' प्रदर्शित की तो तुम्हारे सिनेमा हॉल को आग लगा दी जाएगी." उसके बाद टेलीफोन पर कहा गया, "तुमने हमारी चेतावनी पर अमल नहीं किया, अब नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहो." इसलिए 12 फरवरी को अंततः जब 'शहंशाह' रिलीज हुई तो धमकियों से डरे हुए देश भर के लगभग 242 सिनेमा मालिकों को किसी गड़बड़ी से बचने के लिए भारी संख्या में स्टेनगनधारी पुलिस वालों की सहायता लेनी पड़ी.

लंबे समय से प्रतीक्षित इस फिल्म को देखने के लिए दर्शकों की अपार भीड़ उमड़ पड़ी. अमिताभ बच्चन की इस विवादास्पद फिल्म की एडवांस बुकिंग ने अब तक के सारे रिकार्ड तोड़ दिए. दिल्ली के एक भीड़भाड़ वाले इलाके में 'शीला' सिनेमा हॉल में पहला शो देखने के लिए सुबह 9 बजे से ही लोग जुटने लगे थे. सिनेमा मालिक अजय कौशीश का कहना था, "किसी फिल्म के लिए इतनी ज्यादा भीड़ आज तक नहीं देखी गई."

उधर कुछ विपक्षी पार्टियों और संगठनों की युवा शाखाएं इस बात के लिए कमर कसे बैठी थीं कि वे इस फिल्म को प्रदर्शित नहीं होने देंगी, क्योंकि उनके विचार में अमिताभ भ्रष्टाचार के प्रतीक बन गए हैं. दूसरी ओर फिल्म उद्योग के लोग भी कम डरे हुए नहीं थे. उन्हें आशंका थी कि यह फिल्म प्रदर्शित भी हो पाएगी या नहीं और हो भी गई तो पता नहीं कैसी चल पाएगी. निर्माता टीनू आनंद ने अंततः फिल्म को देश भर के 242 सिनेमा हॉलों में एक साथ रिलीज कर ही दिया. आश्चर्यजनक बात यह है कि बंबई टेरीटरी में इस फिल्म के वितरण का अधिकार अमिताभ ने आखिरी क्षणों में छोड़ दिया. यह अधिकार वे काफी दिनों से अपने पास रखे हुए थे.

बहरहाल, 12 फरवरी को फिल्म रिलीज होने के बाद खबरें आनी शुरू हुईं कि परदे पर अमिताभ को देखते ही तालियां बजीं, कि ब्लैक में टिकटों की कीमत 100 रुपए से भी ऊपर चली गई वगैरह-वगैरह.

और तो और, इस फिल्म के वीडियो कैसेटों की बिक्री भी धड़ल्ले से हुई. पांच दिन पहले से ही इसकी एडवांस बुकिंग होने रही. कहा जा रहा है कि वीडियो पर एक मिनट के विज्ञापन के लिए विज्ञापन दाताओं ने कई लाख रुपए दिए. बनारस में एक थियेटर ने रविवार की सुबह सात बजे का एक अतिरिक्त शो चलाया और जैसे लोगों की बाढ़ हॉल में घुस गई 'इवनिंग न्यूज' के फिल्म समीक्षक ने लिखा, "शहंशाह से जुड़ी हर चीज तो जैसे सोना बना रही है."

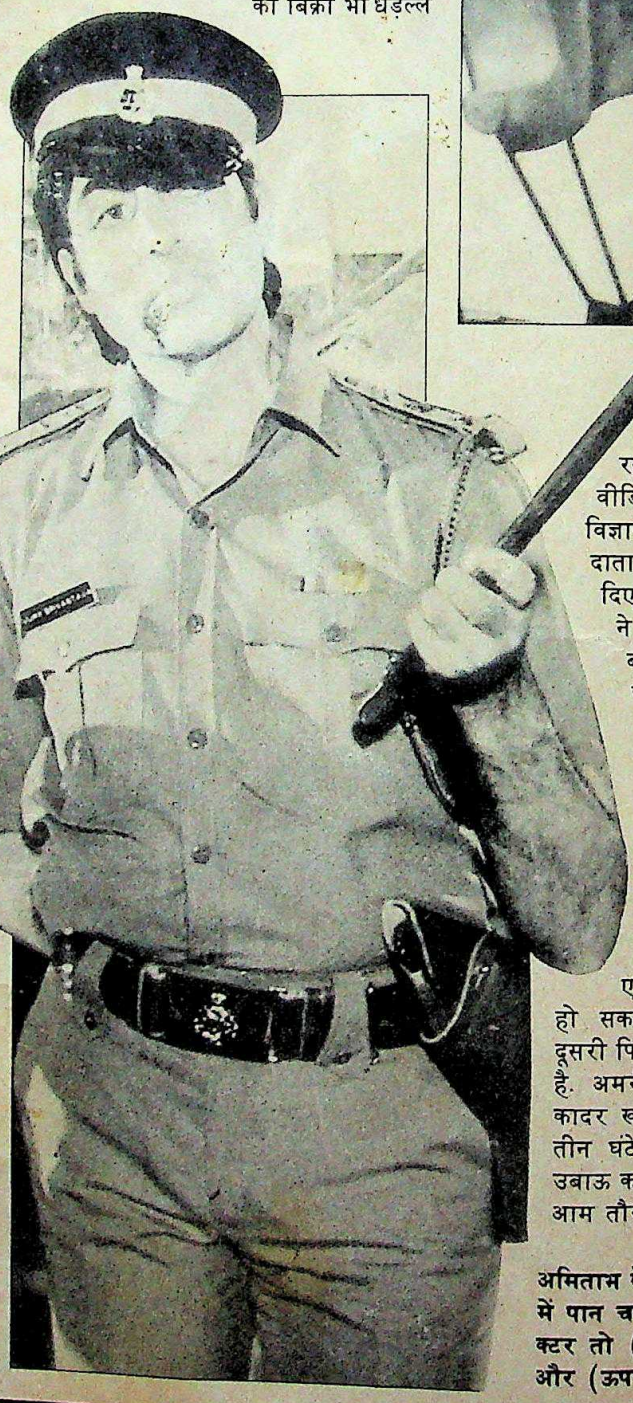

यह फिल्म, जो फिल्म उद्योग के लिए एक भारी झटका साबित हो सकती थी, अमिताभ की दूसरी फिल्मों से कतई अलग नहीं है. अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा, कादर खान और अरुणा ईरानी तीन घंटे तक उसी घिसी-पिटी उबाऊ कहानी को दोहराते हैं जो आम तौर पर फार्मूला फिल्मों में

अमिताभ के दो रूप—(बाएं) बिहार में पान चबाने वाले मसखरे इंस्पेक्टर तो (दाएं) रात में शहंशाह और (ऊपर) मीनाक्षी: वही लटके

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तरीन हीरोइन मीनाक्षी शेषाद्री है, जो रहती तो झोंपड़पट्टी में है लेकिन कपड़े ऐसे पहनती है कि अच्छे-से-अच्छे ड्रेस डिजाइनर को भी सबक सिखा दे. और शहंशाह तो बस शहंशाह ही है—अपने आप में ही एक कानून, पुलिस और अदालत सब की पहुंच से परे. फिल्म वितरक राज चोपड़ा पूछते हैं, "दर्शकों को भला और चाहिए भी क्या?"

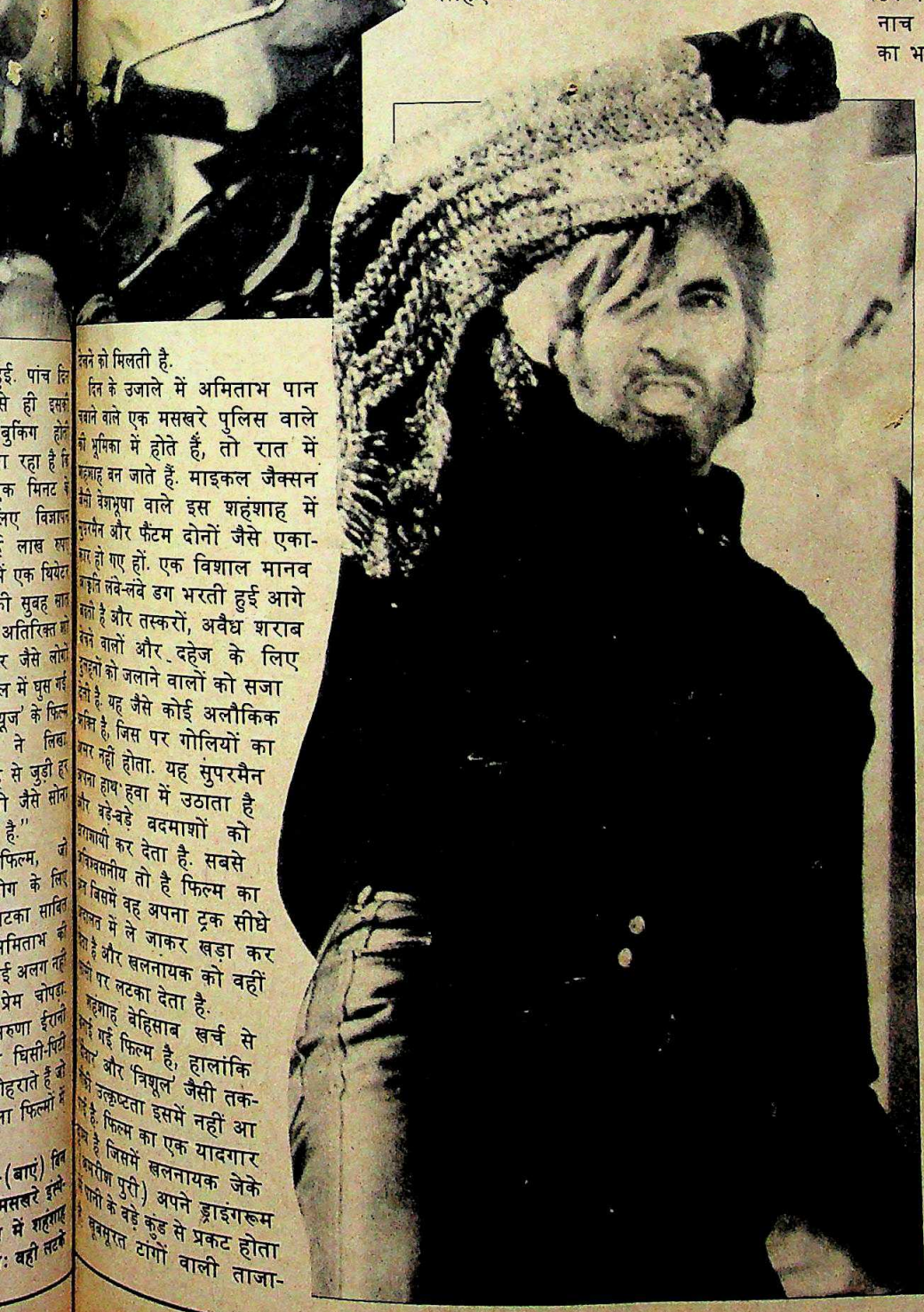

देखने को मिलती है.

दिन के उजाले में अमिताभ पान चबाने वाले एक मसखरे पुलिस वाले की भूमिका में होते हैं, तो रात में शहंशाह बन जाते हैं. माइकल जैक्सन जैसी वेशभूषा वाले इस शहंशाह में सुपरमैन और फैंटम दोनों जैसे एकाकार हो गए हों. एक विशाल मानव आकृति लंबे-लंबे डग भरती हुई आगे बढ़ती है और तस्करों, अवैध शराब बेचने वालों और दहेज के लिए बहुओं को जलाने वालों को सजा देती है. यह जैसे कोई अलौकिक शक्ति है, जिस पर गोलियों का असर नहीं होता. यह सुपरमैन अपना हाथ हवा में उठाता है और बड़े-बड़े बदमाशों को हवालात में ले जाकर खड़ा कर देता है और खलनायक को वहीं फांसी पर लटका देता है.

शहंशाह बेहिसाब खर्च से बनाई गई फिल्म है, हालांकि 'शोले' और 'त्रिशूल' जैसी तकनीकी उत्कृष्टता इसमें नहीं आ पाई है. फिल्म का एक यादगार दृश्य है जिसमें खलनायक जेके (अमरीश पुरी) अपने ड्राइंगरूम की छत के बड़े कुंड से प्रकट होता है. खूबसूरत टांगों वाली ताजा-तरीन हीरोइन मीनाक्षी शेषाद्री है, जो रहती तो झोंपड़पट्टी में है लेकिन कपड़े ऐसे पहनती है कि अच्छे-से-अच्छे ड्रेस डिजाइनर को भी सबक सिखा दे. और शहंशाह तो बस शहंशाह ही है—अपने आप में ही एक कानून, पुलिस और अदालत सब की पहुंच से परे. फिल्म वितरक राज चोपड़ा पूछते हैं, "दर्शकों को भला और चाहिए भी क्या?"

फिल्म प्रदर्शक सिद्धेश्वर दयाल कहते हैं, "अमिताभ ने सिद्ध कर दिया है कि वे अभी भी 'नंबर वन' हैं, उनके विरोधी फिल्म दो ही दिनों में बिक गई. शहंशाह में अमिताभ ने अपने सभी पुराने लटके-झटके कायम रखे हैं. फिल्मी दुनिया के शायद वही एकमात्र हीरो हैं, जिन्हें तेल-चुपड़े बालों में कैमरे के सामने आने में कोई एतराज नहीं. मुंह के कोने से बहती पान की पीक, भौंडे, बेढब कपड़े, कूल्हे मटकाने वाले फूहड़ नाच इन सबके बावजूद उन्हें लोगों का भरपूर प्यार मिला है. अमिताभ इसलिए विशिष्ट हैं कि वे लोगों को बिलकुल जाने-पहचाने लगते हैं.

फिल्म के निर्देशक टीनू आनंद कुछ महीने पहले लगभग दिवालिए हो चले थे, और छोटी-छोटी विज्ञापन फिल्मों के निर्माण पर उतर आए थे. फिल्म प्रदर्शक भी मंदी के दौर से गुजर रहे थे. अब कई महीनों में पहली बार ऐसा हुआ है कि दर्शक सिनेमाघरों की ओर उमड़ने लगे हैं.

घरों की ओर उमड़ने लगे हैं.

अभी से नहीं कहा जा सकता कि फिल्म अंततः कैसा धंधा करेगी. जब तक सिनेमा हॉल पर दर्शकों की भीड़ छंट नहीं जाती यह हिट ही नजर आ रही है. लेकिन फिल्म उद्योग दो धड़ों में बंटा हुआ है. यह फिल्म अब तक की सबसे महंगी फिल्म है. वितरक प्रत्येक टेरीटरी के लिए 90 लाख रुपए दे रहे हैं. भाग्य ने अमिताभ को एक सुनहरा मौका दिया है और निर्माता मधुमक्खियों की तरह उसके इर्द-गिर्द मंडराने लगे हैं. खबर है कि उन्होंने पिछले महीने 12 फिल्में साइन कीं. लेकिन अब अमिताभ बूढ़े लगने लगे हैं. चोपड़ा कहते हैं, "वह प्रकृति से तो नहीं लड़ सकता." और कटु सत्य भी यही है कि यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे अमिताभ नहीं जीत सकते.

—सिमरन भार्गव

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मिलेगी मजबूत छत

● सरल और सस्ती तकनीक के बहुत कम ग्राहक होते हैं. लेकिन त्रिवेंद्रम की क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा विकसित नारियल के पत्तों के छप्पर की जीवन अवधि एक साल से बढ़ाकर तीन साल करने की तकनीक की काफी मांग है. छप्पर में काम आने वाले पत्ते आम तौर पर बरसात और गर्मी के कारण और फफूंद के आक्रमण से नष्ट हो जाते हैं.

डॉ. सी.के.एस. पिल्लै के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने दिखाया कि यदि गुंथी हुई पत्तियों को कॉपर सल्फेट के घोल में डालकर, सुखाकर और उस पर काजू के खोल का घोल छिड़का जाए तो छप्पर काफी दिनों तक चलता है. प्रयोगशाला के 51 वर्षीय निदेशक डॉ. ए.डी. दामोदरन के अनुसार इस पर 8.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की लागत आती है. यह सामान्य तौर पर आने वाली प्रति वर्ग मीटर 5.32 रुपए की लागत से अधिक जरूर है लेकिन ज्यादा समय चलने के कारण मंहगा पड़ता है. वैज्ञानिकों को इस बात से संतोष हुआ होगा कि इसे उपयोग करने वाले अधिक लागत से नहीं घबराए, बल्कि वे छप्पर लंबे समय तक टिके रहने की क्षमता से प्रभावित दिखे.

छप्पर पर छिड़काव: सस्ती तकनीक

त्रिवेंद्रम की एक स्वयंसेवी संस्था मित्र निकेतन और तमिलनाडु में कन्याकुमारी के विवेकानंद केंद्र ने इस प्रयोग में पहल की. पत्ते परिशोधित करने के लिए केरल में तीन संयंत्र लगाए गए हैं. इस राज्य के छप्परों वाले 20 लाख घरों के लिए ही करीब 40 करोड़ पत्ते चाहिए. यदि हरेक व्यक्ति अभिक्रिया किए हुए छप्पर इस्तेमाल करने लगे तो इससे 6 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है. 10 वर्ष पुरानी इस प्रयोगशाला के कर्मचारी भी इस तकनीक को लोकप्रिय बनाने में जुटे हुए हैं.

विज्ञान के दीवाने

● तीन महीने तक गली-कूचों में विज्ञान का प्रदर्शन करने के बाद जिस भारत जन विज्ञान जत्थे की यात्रा 7 नवंबर को भोपाल में समाप्त हुई, उसके आयोजक देश भर में विज्ञान टोलियां गठित करने और उनके माध्यम से विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए 11 और 12 फरवरी को केरल के कन्नानूर में मिल बैठे. हाल ही में गठित ऑल इंडिया पीपुल्स साइंस कांग्रेस के संयोजक 53 वर्षीय डॉ. एम.पी. परमेश्वरन ने कहा, "अब हम वार्षिक सम्मेलन किया करेंगे. साल में एक महीना विज्ञान मास के रूप में मनाएंगे."

बाबजी/जनता स्टूडियो

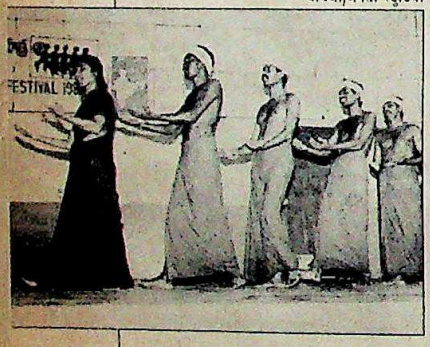

विज्ञान का प्रचार: नए पुरस्कार

जत्थे को आर्थिक सहायता देने वाली राष्ट्रीय विज्ञान और तकनीकी संचार परिषद ने विज्ञान को लोकप्रिय बनाने वाली संस्था और बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करने वाले व्यक्ति को पुरस्कृत करने की घोषणा की. एक लाख रुपए का नेहरू पुरस्कार कर्नाटक राज्य विज्ञान परिषद को और दूसरा 50,000 रुपए का पुणे के अरविंद गुप्ता को मिला.

आंख आकाश में

● 22 दिनों में संसार की सैर. यह कोई अजूबा नहीं है. भारत का रिमोट सेंसिंग उपग्रह आईआरएस-1ए यह करामात कर दिखाने वाला है. वह अंतरिक्ष से भारतीय क्षेत्र के चित्र खींचकर नीचे भेजेगा. 980 किलो का यह उपग्रह 22 मार्च को सोवियत संघ के बेइकानोर प्रक्षेपण स्थल से सूर्य के अनुकूल तथा लगभग गोलाकार कक्षा में वोरतोक बूस्टर रॉकेट द्वारा स्थापित किया जाना है.

22 दिनों की इस परिक्रमा में इसमें लगाए गए अति संवेदनशील कैमरों के दो सेट 904 मीटर की दूरी से 30 मीटर आकार तक की छोटी वस्तुओं को खोजने में सक्षम हैं. यह उपग्रह और जानकारियों के अलावा जमीन के भीतर के पानी के स्रोतों, खनिज भंडारों और जंगलों के फैलाव की भी जानकारी देगा. यह जानकारी देश के राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंध तंत्र से जुड़े 23 केंद्रों के शोधकर्ताओं तक जाएगी.

अभी तक भारत ऐसी जानकारियों के लिए फ्रांसीसी और अमेरिकी उपग्रहों पर निर्भर रहा करता था. लेकिन आइआरएस-1ए को अंतरिक्ष में स्थापित कर दिए जाने के बाद अब ये सूचनाएं लगातार मिल सकेंगी और होने वाले बदलावों पर निगाह रखी जा सकेगी. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के 55 वर्षीय अध्यक्ष प्रोफेसर यू.आर. राव का कहना है कि इसकी सबसे ज्यादा उपयोगिता कृषि क्षेत्र में है. "अगले तीन साल में हमें देश में उगाई जाने वाली छह से आठ फसलों के अच्छे चित्र मिल जाएंगे."

जमीन पर आकाश

● पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए अब हवाई जहाज के कॉकपिट में भेजने की जरूरत नहीं रही है. उन्हें जमीन पर ही एक 'स्थिर मशीन' के जरिये प्रशिक्षित किया जा सकता है. हवाई जहाज के प्रतिरूप वाली 11 करोड़ रुपए लागत की इस मशीन का उद्घाटन पिछले पखवाड़े प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में इंडियन एअरलाइंस के सेंट्रल ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट (सीटीई) में किया. बोइंग के लाइसेंसशुदा पायलट रहे राजीव ने 40 मिनट तक इसे 'उड़ाया'. सीटीई में लगाया गया छह अक्षीय गति सिमुलेटर उड़ान के दौरान आने वाली हर मुश्किल यानी खराब मौसम, तकनीकी नाकामी और इंजन में आग लगने जैसी स्थिति पैदा करने में सक्षम है.

राजीव की 40 मिनट की उड़ान बगैर किसी बाधा के पूरी हुई. प्रबंध निदेशक कैप्टन एन.एस. रामचंद्रन ने कहा, "हालांकि पिछले छह-सात साल से वे उड़ान से दूर रहे हैं पर उनका हाथ सधा हुआ था."

—अमरनाथ के. मेनन

राजीव और नया सिमुलेटर: सधा हुआ हाथ

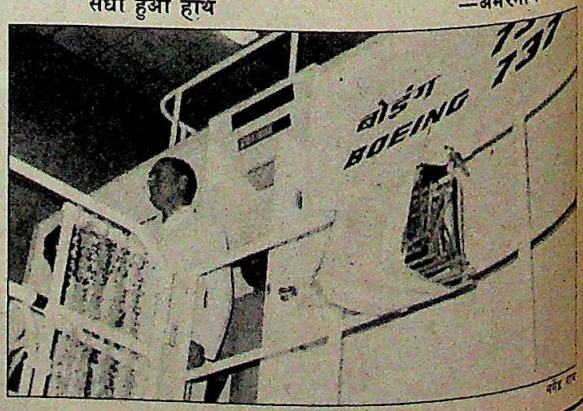

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रिपोर्ताज

विपदा का सटीक चित्रण

भोपाल गैस त्रासदी पर नए नजरिये से विश्लेषण

भोपालः द लेसंस ऑफ ए ट्रेजेडी
संजय हजारिका
पेंग्विन इंडिया
कीमतः 55 रु.
पृष्ठः 230

ए किलिंग विंड
दान कुर्जमेन
मैकग्रा हिल
कीमतः 19.95 डॉलर
पृष्ठः 297

हाल के वर्षों में बहुत कम ही घटनाओं की भोपाल गैस कांड जितने व्यापक पैमाने पर और निरंतर रिपोर्टिंग होती रही है. इसलिए इस मुद्दे पर कलम उठाने वाले लेखक को पूरी किताब में पाठकों को बांधे रखने के लिए नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे. संजय हजारिका की किताब 'भोपालः द लेसंस ऑफ ए ट्रेजेडी' और डाल कुर्जमेन की किताब 'ए किलिंग विंड' में निश्चित रूप से इस हादसे को नए नजरिये से देखने की कोशिश की गई है. हजारिका की किताब एक गंभीर रिपोर्ताज और भोपाल को इस पूरे प्रदूषित विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश है, वहीं कुर्जमेन की किताब किसी रोमांचक उपन्यास जैसी लगती है.

'न्यूयॉर्क टाइम्स' के नई दिल्ली संवाददाता, 34 वर्षीय हजारिका की किताब के आधे पृष्ठों में हादसे और उसके असर का विवरण दिया गया है. इस हादसे पर अपने अखबारं के लिए रिपोर्टिंग कर चुके हजारिका के विवरण में कोई बहुत खास चीज नहीं दिखती.

लेकिन तकनीक और रसायनों के अंधाधुंध उत्पादन के जंजाल में बुरी तरह फंस चुकी दुनिया के सामने उपस्थित दुविधा का विवरण बहुत सटीक है. दुनिया फायदे तो लेना चाहती है पर इसे बनाने की प्रक्रिया में पनपने वाले 'दैत्यों' को नियंत्रित रखने में परेशानी महसूस करती है.

भारत में जिस तरह रसायनों के उत्पादन, भंडारण और रखरखाव में बहुत सावधानी नहीं बरती जाती, उस हिसाब से यह बात खास महत्व की है. भारत में 78,000 टन कीटनाशकों का उत्पादन होता है और इनमें 70 फीसदी ऐसे हैं जिनके उत्पादन पर पश्चिम में रोक लगा दी गई है. भारत के लोगों के शरीर में डीडीटी की मात्रा भी दुनिया में सबसे अधिक (प्रति दस लाख में 12.8 से 31 अंश तक) है. कीटनाशकों का आंख मूंदकर इस्तेमाल करने से ऐसा हुआ है.

गड़बड़ी का दोष बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दिया जा सकता है. पर असलियत यही है कि विकासशील देशों की सरकारी और निजी कंपनियों के सुरक्षा रिकार्ड भी कोई बहुत बढ़िया नहीं हैं. हजारिका ने इस संदर्भ में मलेशिया और फिलीपीन के सर्वेक्षणों का हवाला दिया है. भारत में ऐसा कोई सर्वेक्षण तो नहीं हुआ है पर सिर्फ महाराष्ट्र में ही प्रदूषण फैलाने वाली 6000 इकाइयों का होना स्थिति की गंभीरता को ही बताता है.

'वाशिंगटन पोस्ट' के पूर्व विदेश संवाददाता कुर्जमेन को ऐसी बातों पर ध्यान देने का वक्त कम ही है. यूनियन कारबाइड के अध्यक्ष वारेन बी. एंडरसन द्वारा वाशिंगटन के एक होटल के कमरे में झूठ बोलने से उन्होंने अपनी कहानी शुरू की है. एंडरसन हों या भोपाल स्थित प्लांट के पास रहने वाले सयासी, सबका चरित्र उन्होंने बड़ी खूबसूरती से उभारा है और यही इस किताब में पढ़ने लायक है.

हादसे से पीड़ित शहर में पहुंचने वाले अमेरिकी वकील जॉन कोल का चरित्र उन्होंने बड़ी अच्छी तरह उभारा है और उन्हें वे 'एंबुलेंस चेजर' कहते हैं. कोल भागे-भागे भोपाल पहुंचते हैं और अमेरिका में बसा एक भारतीय दर्जी उनका दलाल बनकर साथ ही आता है. एक विवरण कोल की कमीजों का है. लोगों पर रौब गांठने के लिए वे 540 डालर (7020 रुपए) में नौ कमीजें खरीदते हैं. आठ तो फिट नहीं आतीं और नौवीं के सारे बटन एक साथ टूट जाते हैं. और जिन लोगों पर वे रौब गालिब करना चाहते हैं, उनके सामने ही उनकी छाती नंगी हो जाती है.

कुर्जमेन के इस खूबसूरत विवरण में किरकिरी बन गई हैं कुछ भूलें. जैसे उन्होंने भारत में वनवासियों की संख्या 3.3 लाख, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक हिंदू संप्रदाय, नर्मदा को नरबादो और राजीव गांधी को अर्जुन सिंह का दोस्त बता दिया है. भारत का उनका ज्ञान ही उन्हें धोखा दे गया है. इससे भी बड़ी गड़बड़ मरने वालों की संख्या की है. सरकार कहती है 2,850 लोग मरे जबकि उनका मानना है कि मरने वालों की संख्या करीब 8,000 है. पर इसका कोई पुख्ता सबूत वे नहीं दे पाए हैं.

—श्रीकांत खांडेकर

अनिल मित्र

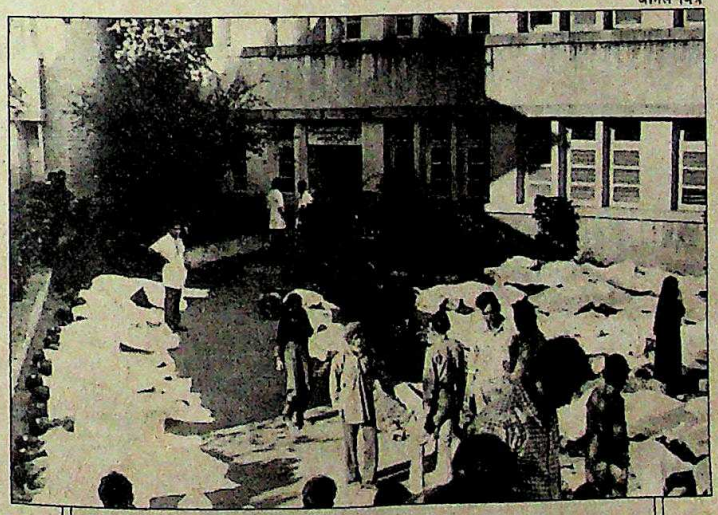

भोपाल के गैस पीड़ितः प्रदूषित दुनिया के मारे

जहां हजारिका भोपाल त्रासदी को दुनिया के प्रदूषण के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, वहीं कुर्जमेन की किताब रोमांचक उपन्यास जैसी लगती है

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पीआईबी

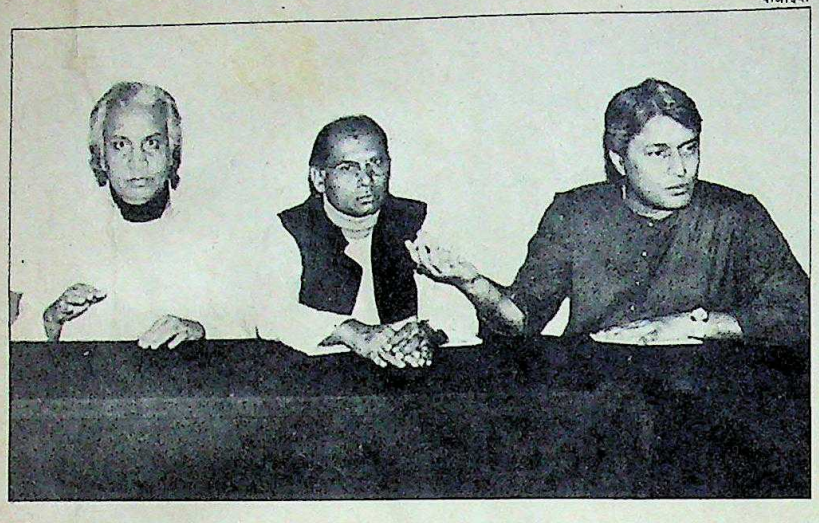

पत्रकार वार्ता में (बाएं से) डागर, असद अली खां और अमजद अली खां: विरोध

रईस खां

आखिर घुंघरू टूट गए

पर मुल्क के मशहूर फ़नकारों ने विरोध जताया

कुछ साल पहले लंदन के रायल अलबर्ट हॉल में भारत के एक मशहूर सितार-वादक ने सितार को किनारे रखते हुए एक गज़ल गाई जिसके बोल थे: "मोहे आई न जग से लाज, मैं इतना जोर से नाची आज कि घुंघरू टूट गए." गजल पेश करने की अदा व शोखी पर हॉल में मौजूद एशियाई श्रोता अपनी सीटों से उछल पड़े. लेकिन पिछले पखवाड़े कराची की एक अंग्रेजी पत्रिका 'मैंग 88' में छपे इस फनकार के बयान ने जो माहौल पैदा किया उससे लगा मानो लोक-लाज को एक किनारे रख और घुंघरुओं को पटककर कोई कलाकार नंगा नाचने के लिए मंच पर जा चढ़ा हो.

भारत से नाता तोड़कर पिछले कुछ समय से पाकिस्तान जा बसे उस्ताद रईस खां ने आरोप लगाया कि भारत में मुसलमान शास्त्रीय संगीतकारों के साथ बहुत भेदभाव बरता जा रहा है और संगीत पर सिर्फ हिंदू कलाकारों का कब्जा हो गया है. रईस खां ने यहां तक कह डाला कि मुसलमान कलाकारों की उपेक्षा के कारण जल्दी ही भारत से शास्त्रीय संगीत का सफाया हो जाएगा. उन्होंने बताया कि इसी चिंता के मारे उन्होंने भारत छोड़कर पाकिस्तान में बसने का फैसला कर लिया है. रईस खां इन दिनों अपनी चौथी पत्नी और मशहूर पाकिस्तानी गायिका बिलकिस खानम के साथ कराची में रह रहे हैं और ज़िया सरकार से पाकिस्तानी नागरिकता मिलने की इंतजार कर रहे हैं.

भारतीय संगीत जगत में इस बयान पर प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक ही था. लेकिन मजेदार बात यह रही कि रईस खां के आरोपों का जवाब देने की पहल जिन पांच फनकारों ने की वे सभी मुसलमान हैं और अपने-अपने फन में प्रसिद्धि की बुलंदियों पर हैं. सरोदवादक अमजद अली खां, रुद्रवीणा-वादक असद अली खां, तबलावादक शफात अहमद खां और ध्रुपद गायक डागर भाइयों की जोड़ी—उस्ताद फैयाजुद्दीन डागर और उस्ताद जहीरुद्दीन डागर—ने तुरत-फुरत दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन बुला डाला. अपने साझा बयान में उन्होंने रईस खां के बयान को 'बेबुनियाद' और 'झूठा' बताते हुए जवाबी आरोप लगाया कि पाकिस्तान की नागरिकता हासिल करने के लिए ही वे ऊल-जुलूल बातें कर रहे हैं.

अपने साझा बयान में उन्होंने पाकिस्तान सरकार की शास्त्रीय संगीत के प्रति सांप्रदायिक नीतियों की आलोचना करते हुए यह घोषणा भी कर डाली कि वे भविष्य में पाकिस्तान का बहिष्कार करेंगे और वहां अपना कोई कार्यक्रम पेश नहीं करेंगे. उस्ताद हाफ़िज़ अली खां, मुश्ताक हुसैन खां, अलाउद्दीन खां, फ़ैयाज़ खां और जाकिर हुसैन जैसे कई नाम गिनाते हुए इन फनकारों ने कहा कि भारत की जनता और सरकार ने जो प्यार और इज्जत इन फनकारों को दी है उसकी पाकिस्तान में कल्पना भी नहीं की जा सकती. उस्ताद असद अली की शिकायत थी कि भारत आने वाले पाकिस्तानी कलाकारों को तो सिर आंखों पर बिठाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान जाने वाले भारतीय कलाकारों को उनके से मिलने के लिए भी वहां घुसने नहीं दिया जाता.

अमजद अली ने भी रईस खां के बयान को 'देश के साथ गद्दारी' बताते हुए पूछा "अपनी कमजोरियों को किसी और के मत्थे मढ़ना कहां की बहादुरी है?"

यह पहला मौका नहीं जब रईस खां किसी विवाद के घेरे में फंसे हों. मशहूर बीनकार और जिंदगी के आखिरी दौर में हाथ के लकवे से परेशान अपने पिता उस्ताद मुहम्मद खां से 'किसी भी तरह की तालीम न मिलने' की शिकायत करके; अपने मामा विख्यात उस्ताद विलायत खां को 'अपने यहां का शागिर्द' बताकर; और उन पर फ़िदा चांद बाला से व्याह करके वे पहले भी कई बार सार्वजनिक चर्चा का केंद्र बन चुके हैं. एक बार बंबई में उन्होंने विलायत खां को सार्वजनिक मुकाबले में चुनौती दे डाली. मगर मुकाबले में विलायत खां ने ऐसा रंग जमाया कि रईस खां बुरी तरह पिट गए.

पर इस सबके बावजूद उनके गले की मिठास और सितार के फन ने उन्हें बंबई की फिल्मी दुनिया में खासा नाम और दाम कमाने का मौका दिया. लेकिन यह सब करते हुए शास्त्रीय संगीत पर उनकी पकड़ जाती रही. फिल्मी दुनिया से उनका परिचय कराने में इमरजेंसी में चर्चित रुखसाना सुलताना का सहयोग काफी काम आया. 15-20 वाद्यों के विशाल आर्केस्ट्रा के साथ गज़ल पेश करने की परंपरा का श्रेय भी काफी हद तक रईस खां को ही जाता है. बाद में 1979 के दौरान अपनी पाकिस्तान यात्रा में बिलकिस खानम पर वे ऐसे फिदा हुए कि उन्हें अपनी चौथी पत्नी बना लिया और उनके साथ पांच साल तक बंबई में रहने के बाद पाकिस्तान चले गए.

एक होनहार भारतीय कलाकार के इस बदले हुए रुख पर उस्ताद अमजद अली खां की यह टिप्पणी बहुत माफिक बैठती है: "दरअसल उनका हाथ सुर में है, गला सुर में है, बस ज़ेहन और ज़ुबान ही बेसुरे हो रहे हैं. ....उनकी तकलीफ तो खुदा ही दूर कर सकता है. खुदा उनके इस गुनाह को माफ करे." आमीन!!!

—मंजरी सिंह

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अपनी आय बढ़ाइए – आयकर नहीं

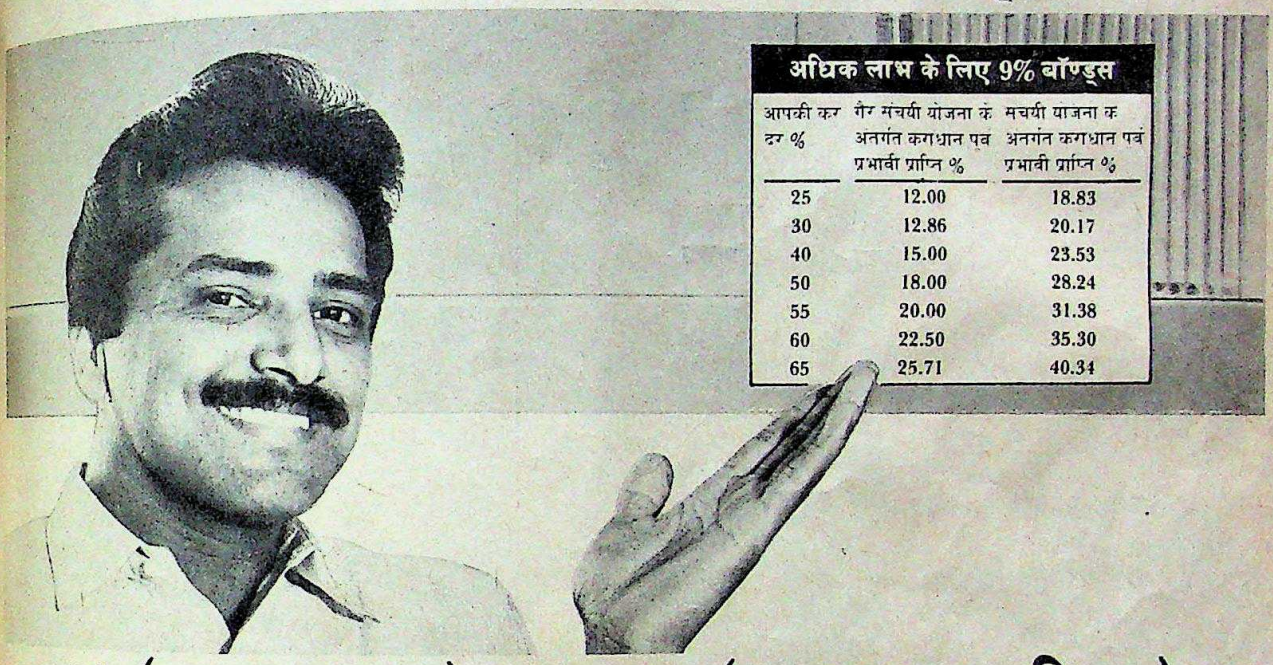

अधिक लाभ के लिए 9% बॉण्ड्स

आपकी कर दर %	गैर संचयी योजना के अन्तर्गत करोधान पर प्रभावी प्राप्ति %	संचयी योजना के अन्तर्गत करोधान पर प्रभावी प्राप्ति %
25	12.00	18.83
30	12.86	20.17
40	15.00	23.53
50	18.00	28.24
55	20.00	31.38
60	22.50	35.30
65	25.71	40.34

9% (कर-मुक्त) व 13% (कर छूट सहित) एन.टी.पी.सी. पावर बॉण्ड्स

9% (कर-मुक्त) बॉण्ड्स

- सभी करदाताओं के लिए ब्याज बिना सीमा के आयकर मुक्त
- संचयी योजना के अन्तर्गत कुल ब्याज रु. 1412/- वार्षिक प्राप्ति दर 14.12%
- आबंटन तिथि के तीन वर्ष बाद छोटे निवेशकों से सममूल्य पर वापस क्रय की सुविधा
- 10 वर्ष बाद सममूल्य पर विमोचन

साथ ही पेश हैं – 13% बॉण्ड्स

- आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80L के अन्तर्गत ब्याज कर-मुक्त
- संचयी योजना के अन्तर्गत कुल ब्याज रु. 1415/- वार्षिक प्राप्ति दर 20.21%
- आबंटन तिथि के एक वर्ष बाद छोटे निवेशकों से सममूल्य पर वापस क्रय की सुविधा
- 7 वर्ष बाद सममूल्य पर विमोचन

और अनेक समान विशेषताएं

- निवेश पूर्णतया सम्पत्ति कर से मुक्त
- स्रोत पर आयकर की कटौती नहीं
- खैराती एवं धार्मिक निधियों को आयकर में विशेष लाभ
- ब्याज की दो योजनाएं: संचयी एवं गैर-संचयी
- संचयी योजना के अन्तर्गत ब्याज छमाही जोड़ा जाएगा
- गैर-संचयी योजना के अन्तर्गत बॉण्ड्स के साथ ही छमाही, उत्तर-दिनांकित ब्याज वारंट पेशगी भेजे जाएंगे जिनका स्वतः ही निर्धारित तिथि पर भुगतान लिया जा सकता है
- आवेदन पत्र के साथ प्राप्त धन की वसूली की तारीख ही ब्याज देय
- पृष्ठांकन और सुपुर्दगी द्वारा आसानी से हस्तान्तरणीय
- हस्तांतरण स्टैम्प ड्यूटी से मुक्त
- देश के 7 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों की सूची में दर्ज
- कंपनी की सम्पत्तियों द्वारा पूर्णतया सुरक्षित
- बोली गारंटियों/बयाना एवं जमानत के तौर पर एन.टी.पी.सी. द्वारा स्वीकार्य

40,00,000 सिक्योर रिडिमेबल, रु. 1000 प्रत्येक के 9% (कर-मुक्त) एवं 13% बॉण्ड्स का सममूल्य पर सार्वजनिक निर्गम – कुल राशि रु. 400 करोड़

निर्गम आरम्भ : 10 मार्च 1988
निर्गम समाप्ति : 19 मार्च 1988

निर्गम के प्रबंधक

एन. सी. आई. कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड
202, मेकर टावर्स 'ई' 2री मंजिल, कफ परेड बम्बई-400 005

कैनबैंक फाइनेन्शियल सर्विसेज लि
1-ई, बन्दना बिल्डिंग, टॉलस्टाय मार्ग नई दिल्ली-110 001

NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लि.
(भारत सरकार का उपक्रम)
पंजीकृत कार्यालय : एन.टी.पी.सी. स्क्वायर, 62-63, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110 019

Sobhagya/42/88/H

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

छायालेख: रघु राय Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सधी थापों के

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

थिरकते बोल

करीब पांच दशकों से अल्लारक्खा ने लयों और छंदों की अपनी उत्कृष्ट निपुणता से दुनिया भर के श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किए रखा है. उन्होंने तबला वादन को कलात्मक अभिव्यक्ति की अप्रतिम ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है. अब उनके विलक्षण प्रतिभासंपन्न बेटे जाकिर हुसैन अपने पिता के पदचिन्हों पर बखूबी आगे बढ़ रहे हैं. दुनिया भर के खचाखच भरे सभागारों में कार्यक्रम देने वाले पिता-पुत्र के खास रिश्ते, कला के नित नए शिखरों को चूमने की उनकी सतत साधना का परिचय करा रहे हैं फीचर संपादक इंद्रजीत बधवार. *यह लेख भारतीय कला और संगीत की महान विभूतियों पर प्रस्तुत की जा रही शृंखला की ही एक कड़ी है*

idwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कभी मौज में आकर तो कभी अचानक तेजी से, कभी असीम आनंद में डूबकर तो कभी बड़ी पटुता और कौशल से वे अपने समूचे अंग-प्रत्यंग को ही ताल और लय की शानदार डोर में बुन डालते हैं. समुद्री हवा के तेज झोंके शक्ति भरी थापों से बंबई स्थित अपार्टमेंट के दूसरे माले को गुंजा देते हैं. आमने-सामने बैठे दो कलाकारों की उंगलियां जिन ध्वनियों का सृजन कर रही हैं वे किसी जादू से कम नहीं हैं. अल्लारक्खा के गंजे सिर के पिछले हिस्से से निकली कंधों तक झूलते घुंघराले बालों की लटें हवा के झोंकों में नृत्य कर रही हैं. उनका ऊपरी होंठ खुले हुए मुंह पर अर्द्धचंद्र की तरह लटका हुआ है. नथुने घोड़े के नथुनों की तरह फैले हुए हैं. पर बेटे की तरफ देखते ही उनके चेहरे पर हमेशा छाया रहने वाला दिल्लगी का भाव अपूर्व संतोष के परमानंद में बदल जाता है.

पिता और पुत्र जुगलबंदी के जरिये मानो द्वंद्व ही करते हैं. पुत्र शंकाएं उठाता है, पिता उनका निवारण करते हैं. बेटा ताल से अठखेलियां करता है, पिता उसे पटरी पर ले आते हैं. ताल और हवा के झोंकों के साथ जाकिर हुसैन का घुंघराले बालों से आच्छादित सिर उठता और झुकता है. उनमें जैसे किसी उन्मुक्त अश्व-सी अबाध सामर्थ्य है. फिर दोनों के चेहरों के भावों में एक लयात्मक समानता दिखने लगती है. उसमें रहस्यात्मक ढंग का कौतुक भी छिपा है. फिर मुस्कराहट पसरने लगती है. आंखें विस्मय और आनंदातिरेक में फैल जाती हैं, त्योरियां चढ़ जाती हैं. जटिल संरचना के बाद लय का चक्र अब पूरा ही होने वाला है. कुछ ही सेकेंडों के भीतर ताल एकदम माकूल लय पर खत्म होने जा रहा है. सिर पीछे की तरफ झुकते हैं. गणितीय परिशुद्धता के साथ रचना पूरी हो जाती है. वे बहुत उत्साह से अपना-अपना सिर हिलाते हैं मानो कलात्मक यात्रा की समाप्ति का संकेत कर रहे हों. फिर वे अलग हो जाते हैं.

उनके भाव सहजता से एक दूसरे में मिल जाते हैं. उम्र कोई बाधा नहीं है. अब यह चार हाथों वाला एक शरीर है. आवाज और भावना का एक चक्रवात. तबला बोलता है, वे गाते हैं, उनकी प्रतिध्वनियां गूंजती हैं. अब जाकिर एक रचना की शुरुआत करते हैं और अल्लारक्खा उसे बड़ी सहजता से समझ लेते हैं, उसमें फेरबदल करते हैं. और फिर जाकिर की तरफ उसे उछाल देते हैं. जाकिर उछालते

अल्लारक्खा के शागिर्द उनका अनुकरण करते हैं. वे वक्त के पाबंद हैं. तबले से जैसे धा धिन धिन धा ता तिन तिन ता, धनी धती धा धा के बोल फूटते हैं वे हर बोल को ध्यान से सुनते हैं

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

के उसे लोक लेते हैं और वापस उछाल देते हैं. वे कभी शरारत से, कभी प्रफुल्लित होकर एक-दूसरे की तरफ ताल बढ़ाते हैं. और फिर सुर एक हो जाते हैं. यह काव्यात्मक लय में सुर-ताल की एक बहुत ही आदर्श तकसीन है.

"हां, यह शरारत है," जाकिर कहते हैं. "मैं सचमुच अपने पिता को छेड़ रहा हूं. मैं जानबूझकर विभ्रम की स्थिति निर्माण करता हूं. उनके मन में किसी रचना का विचार आता है तो कुछ देर तक बजाने के बाद वे उसे मेरी तरफ उछाल देते हैं. मैं उसे ग्रहण कर लेता हूं और जब तक वह लड़खड़ा न जाए उसे बजाता रहता हूं. तब वे उसे वापस लेकर सही मोड़ दे देते हैं. तब मैं उनसे पूछता हूं यह चीज ऐसे क्यों नहीं बज सकती. और वे जवाब देते हैं हां, जाकिर यह चीज वैसी भी सकती है. तब मैं पूछता हूं, क्या यह चीज ऐसी भी हो सकती है? और यह अंतहीन सिलसिला चलता रहता है. सचमुच मैं उनके सामने बालक बने रहकर आनंदित होता हूं."

"मुझे पक्का भरोसा है," अल्लारक्खा कहते हैं, "जाकिर ने अपनी मां के गर्भ में ही तबला सुन लिया था और समझ लिया था कि वह क्या चीज है." पर जाकिर को अपने जन्म से पहले की इस तरह की कोई बात याद नहीं. लेकिन उन्हें याद है, "अपने पिता की आवाज जिसे शायद उन्होंने दो या तीन साल की उम्र में सुना था. मैं स्टेज पर उनके पीछे बैठकर उन्हें तबला बजाते सुना करता था और साथ नहीं ले जाए जाने पर झुंझला जाता था. मुझे याद है कि जब वे दौरे पर चले जाते थे तो मैं रात-रात उनका इंतजार करता रहता. वे देर रात को वापस आते, खाना खाते, फिर हम तबले के बोलों को तब तक गुनगुनाते या तबला बजाते जब तक कि एक साथ ऊंघने नहीं लगते थे. सात साल का होने तक मैं अपने पिता के साथ ही सोता था."

जाकिर कहते हैं, "आप उनसे ज्यादा स्नेही गुरु नहीं पा कसते. तबला छूने से पहले ही मैं उसकी भाषा समझने लगा था. बस मुझे तो उसमें से बोल भर निकालने थे. मैंने बहुत सोच-विचारकर, बहुत प्रयत्नपूर्वक तबला कभी नहीं सीखा."

सैंतीस साल पहले जब जाकिर पैदा हुए थे तो उनके पिता मानो मृत्युशैया पर ही पड़े थे. उनके पिता की उम्र उस समय 30 साल थी. वे किसी अज्ञात बीमारी से लगभग एक साल से बीमार थे. उनके

जाकिर कहते हैं, "आप ऐसा स्नेही गुरु नहीं पा सकते. तबले को छूने से पहले से ही मैं इसकी भाषा समझने लगा था. मुझे सिर्फ बोल निकालना था. मैंने कभी बहुत प्रयत्नपूर्वक तबला नहीं सीखा"

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दोस्त और संबंधी उनके आखिरी दर्शनों के लिए भी आ गए थे. वे एक ही जगह बिना हिले-डुले बैठे रहते थे, सिर भी ऊपर नहीं उठाते थे. जाकिर को पैदा होने के कुछ ही मिनट बाद पिता के पास ले जाया गया. तब मुद्दत के बाद पहली बार अल्लारक्खा ने सिर हिलाया, नवजात बेटे को बांहों में लिया, नाक से उसे छुआ, फिर उसके कानों में तबले के बोल फुसफुसाने लगे, 'ता धिन धिन ता' जाकिर की मां पति की ही सेवा-सुश्रूषा में लगी रहती थीं, लिहाजा शुरू में वे बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाईं लेकिन उसी महीने उनके घर एक साधु आया और उसने कहा कि लड़के पर विशेष ध्यान दो क्योंकि अंततः वही तुम्हारे पति को बचाएगा.

पिता अपने जीवन के उस काल की बातें बताना पसंद नहीं करते. लेकिन जाकिर कहते हैं, "मुझे लगता है कि उसी समय हम दोनों के बीच एक विचित्र परंतु मजबूत बंधन बंध गया था. बचपन में मैं बहुत बीमार रहता था. मेरी बीमारी जितनी बढ़ती जाती, मेरे पिता उतने ही ठीक होते जाते. आखिरकार वे स्वस्थ हो गए और फिर अपनी रचनाधर्मिता में लग गए."

अल्लारक्खा ने पहले से ही काफी नाम कमा लिया था. वे लाला भवानीदास द्वारा स्थापित पंजाबी घराने के अग्रणी प्रतिनिधि के रूप में माने जाने लगे थे. लाला भवानीदास सम्राट अकबर के दरबारी संगीतज्ञों में से एक थे. अल्लारक्खा ने आकाशवाणी के लिए संगीत रचनाएं कीं, हर मशहूर कलाकार के साथ तबला बजाया

अल्लारख्खा ने पांच वर्षों तक हर रोज 8 से 12 घंटे तक रियाज करके तबला वादन सीखा, "कई बार तो मैं 8-8 घंटे तक बिना रुके बजाता रहता था. मुझे तकसीन और लय में निपुणता हासिल करनी थी"

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

महासती अनुसुइया' समेत एक दर्जन से ज्यादा फिल्मों के वे संगीत निर्देशक भी रहे. महासती अनुसुइया में तो उन्होंने गाया भी. लेकिन उन्होंने अभी तक विदेशों में कार्यक्रम देना शुरू नहीं किया था जिससे वे रविशंकर और अली अकबर खां की तरह ही अमेरिकी और यूरोपीय कॉलिज परिसरों में सांस्कृतिक हस्ती बन जाते.

जम्मू के गांव पगवाल में जन्मे अल्लारक्खा को अपनी मातृभाषा डोगरी बोलने में आनंद आता है. उनकी हिंदी पर डोगरी का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है. जब वे हिंदी बोलते हैं तो हिंदी फिल्मों के स्वर्गीय अभिनेता ओमप्रकाश की याद हो आती है. वे एक गरीब परिवार के सात बच्चों में से एक थे. वे जब लगभग आठ साल के थे तो उन्होंने पहली बार पंजाबी घराने के एक कलाकार को दूसरी जगहों के कुछ कलाकारों के साथ तबला बजाते हुए सुना. अल्लारक्खा ने तय कर लिया कि वे भी यही करेंगे. उनके माता-पिता ने उन्हें समझाया कि वे सेना में शामिल हो जाएं लेकिन वे अपनी बात पर अड़े रहे. वे अपने से तबला बजाते और जहां से भी मुमकिन था, बजाना सीखते रहते. और तब बिस्मिल्ला खां और बालाचंदर जैसे दूसरे कलाकारों की तरह अल्लारक्खा को भी आध्यात्मिक अनुभूति हुई. उस समय वे शायद 11 साल के थे. एक आवाज आई कि पास की नदी के पास जाकर बैठो और देखो कि क्या होता है. "मैं हर शाम वहां जाकर पानी के पास घंटों खड़ा रहता. कुछ नहीं हुआ. फिर, एक दिन जबकि मैं कई घंटे से खड़ा था, मैंने एक अजीब सनसनी महसूस की. लगा कुछ होने वाला है. एकाएक मैंने एक प्रकाश देखा. वह धीरे-धीरे उतर

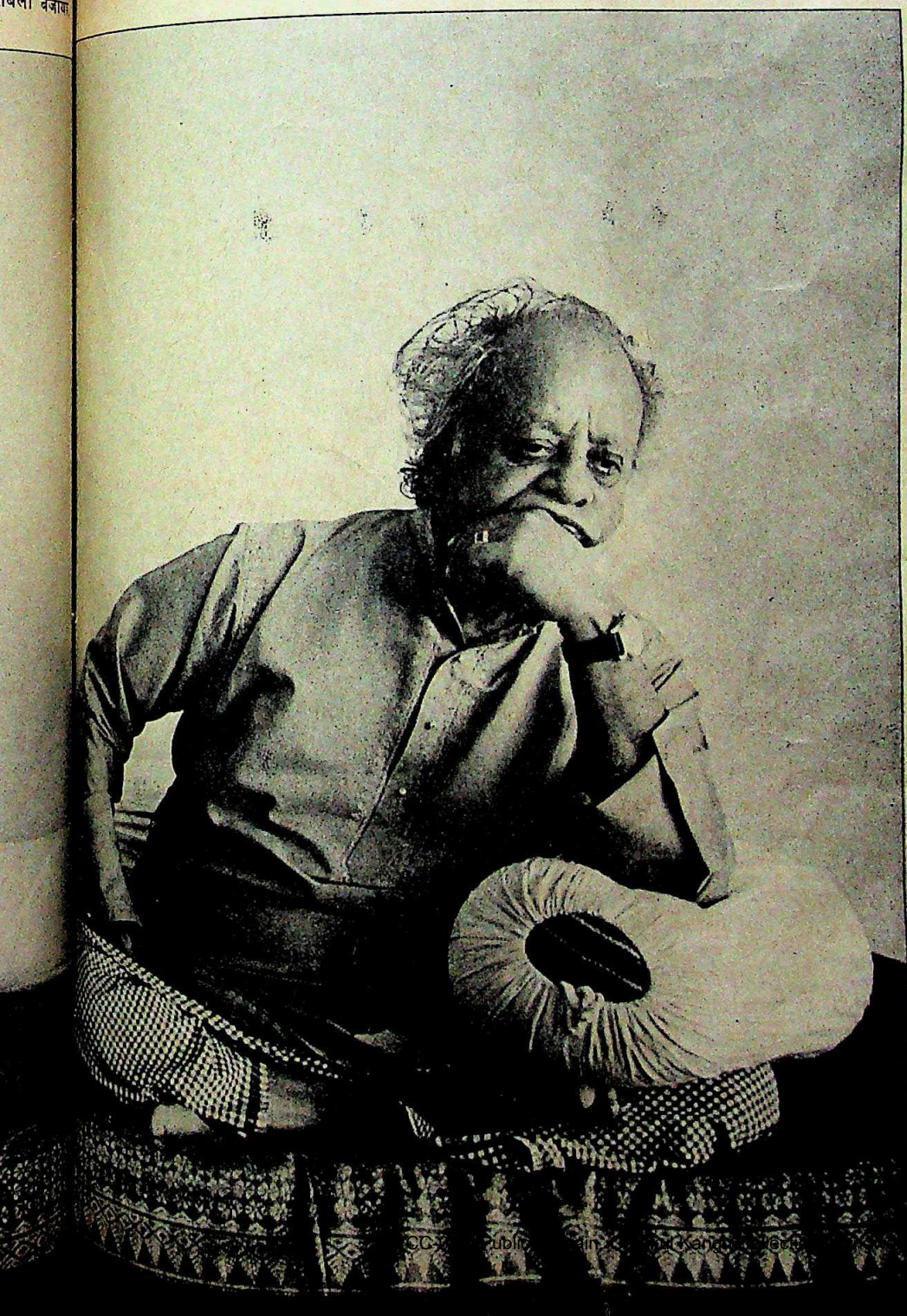

ज़ाकिर को याद है कि पिता से वे हमेशा ईर्ष्या करते थे, "वे ठोस और गहरे बोल निकाल लेते थे. मैं वह गहराई नहीं पा सका था. जो वे एक उंगली से कर देते उसे करने में मुझे पूरे हाथ का इस्तेमाल करना पड़ता था"

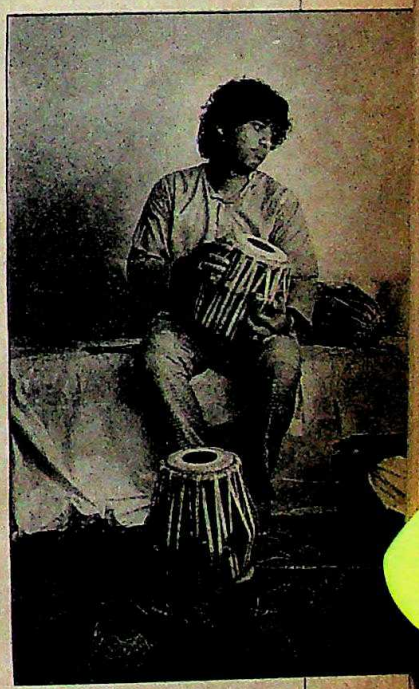

CC-0. Public Domain. Digitized by eGangotri

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रहा था. फिर वह पानी में जाकर अदृश्य हो गया. मैंने डर से आंखें बंद कर लीं. फिर आवाज सुनाई दी, 'जाओ तुमने उसे पा लिया.'

"उसके लगभग तुरंत बाद मैंने अपने भीतर शक्ति का संचार अनुभव किया. मैंने इससे पहले ऐसा कभी अनुभव नहीं किया था. तबले में महारत हासिल करने और भारतीय शास्त्रीय संगीत में तबले को महत्वपूर्ण जगह दिलाने का इरादा इसके पहले इतना मजबूत कभी न था." दो साल बाद, उम्र का तेरहवां साल खत्म होने पर अल्लारक्खा गुरु की खोज में घर से भाग गए. उनके मन में अनिश्चितता थी कि वे शिष्य के रूप में कभी स्वीकार कर लिए जाएंगे भी या नहीं? जिस गुरु की खोज में वे निकले थे वे लाहौर के मियां कादिर बख्श थे. रास्ते में उन्होंने रहने-खाने का खर्च जुटाने वास्ते विभिन्न मंडलियों में तबला बजाया. नौसिखिया लोगों को तबला सिखाने के लिए रास्ते में पड़ने वाली सरायों में वे किराए पर कमरे ले लेते थे. एक बार तो गुरदासपुर में उन्हें इतने छात्र मिल गए कि सिर्फ उन्हें तबला सिखाने से ही उनकी जीविका चलने लगी.

अल्लारक्खा ने लगभग पांच साल तक रोजाना 8 से 12 घंटे रियाज किया. "कभी-कभी तो मैं एक सूती बंडी और [illegible] पहने लगातार आठ घंटे तक तबला बजाया करता. बंडी और [illegible] पसीने से भीग जाती थी. मैं तबले का गणित जानता था लेकिन [illegible] तकसीन और लय में निपुणता हासिल करने के लिए उसका व्याक[illegible] सीखने की जरूरत थी." उन्हें "19 मात्राओं वाला इंद्रताल,

ज़ाकिर कहते हैं, "मैं इसे कोई काम की तरह नहीं लेता. मुझे इसमें बड़ा आनंद आता है. संगीत सभाओं में कैसे बजाया जाता है यह जानने के पहले ही मैं सभाओं में तबला बजाने लगा. मैं जाने बगैर ही पूरी निपुणता से बजाने लगा था"

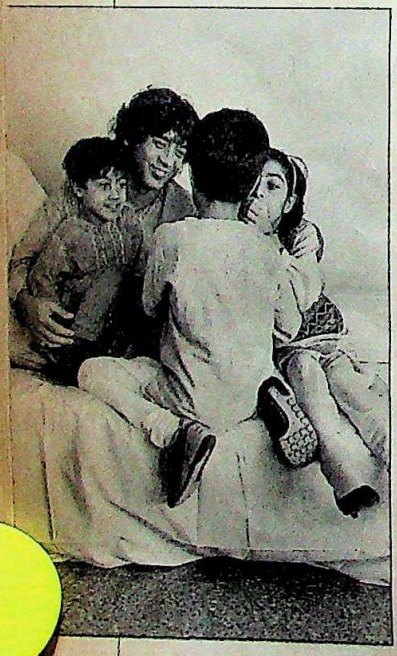

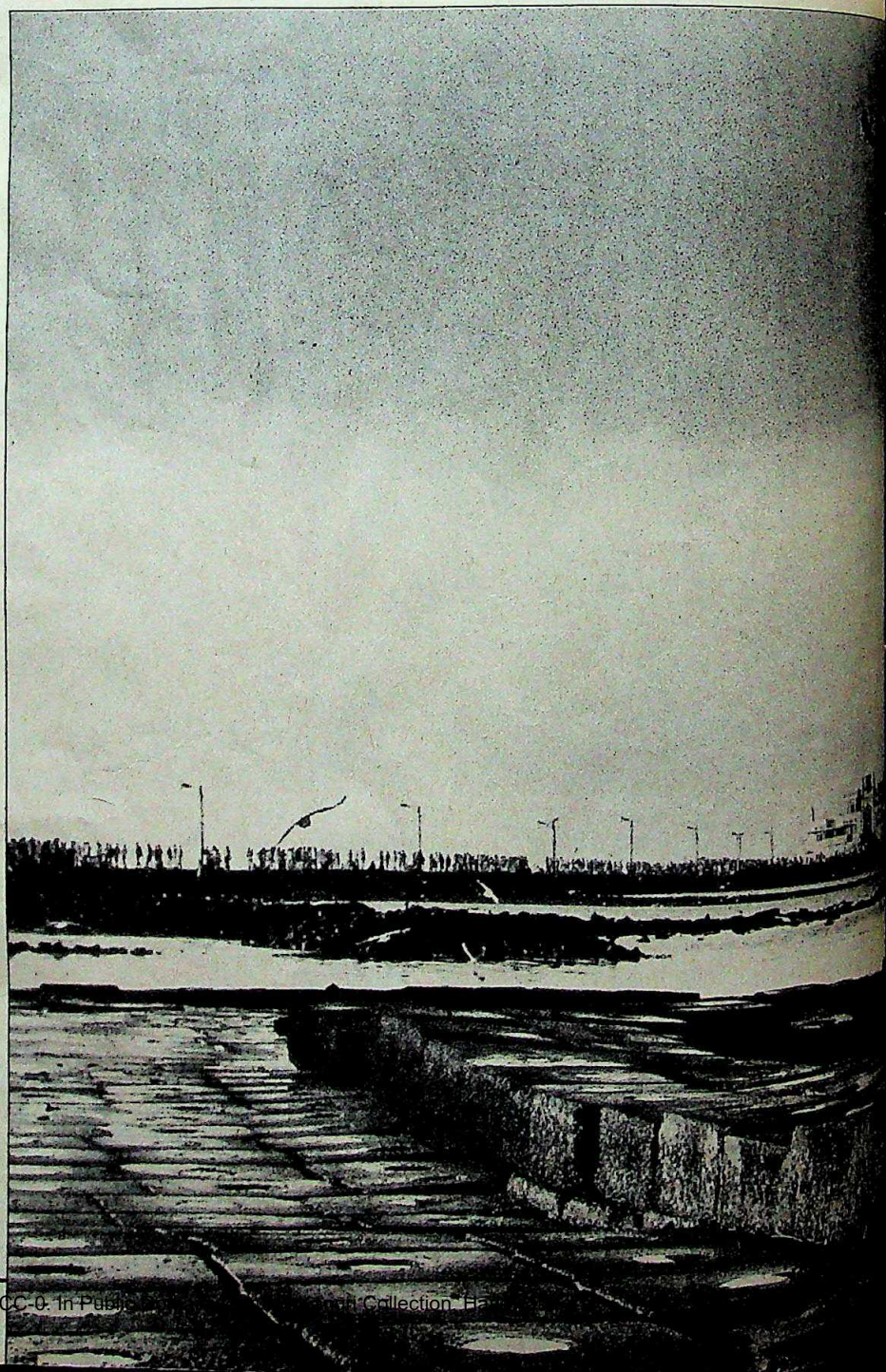

CC-0. In Public [illegible] Collection. Ha[illegible]

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मात्राओं वाला शिखाई ताल और 18 मात्राओं वाले लक्ष्मी और झालवत ताल" सीखने थे और उनमें महारत हासिल करनी थी.

तबले को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सही, वैज्ञानिक और परिष्कृत थाप वाला वाद्य माना जाता है. अल्लारक्खा कहते हैं, पॉप और जाज में इस्तेमाल होने वाले पश्चिमी ड्रम में मूल रूप से केवल एक लय होती है, 1-2-3-4 और 1-2-3-4, बम, बम, बम, बम. वहां ताल नहीं, लय होती है. हमारी तकसीन दी हुई गणितीय सृष्टि पर पूरी होती है जबकि पश्चिम के ड्रम बजाने वाले लोग जब चाहें तब उसे खत्म कर सकते हैं." जाकिर कहते हैं, "सुंदरता और रचनात्मकता, 'तबले में रचनाधर्मिता' सिर्फ जटिल विभाजन और विभाजन करने की तकनीकी कुशलता और योग्यता नहीं है बल्कि जटिल को आसान बनाने की विद्या है."

बिस्मिल्ला खां ने जिस तरह से शहनाई को महत्वपूर्ण जगह दिलाई, ठीक उसी तरह से अल्लारक्खा, किशन महाराज और शामता प्रसाद ने तबले को अद्वितीय रचनात्मक जगह दिलाई. विलायत खां, रविशंकर और अली अकबर खां ने भी तबला कलाकारों को बहुत बढ़ावा दिया. अल्लारक्खा के 35 एलपी हैं जिनमें से कोई आठ एकल हैं. और उनके अधिकतर कार्यक्रम या तो एकल होते हैं या जाकिर के साथ. अल्लारक्खा अभी भी साल में चार महीने विदेश यात्रा पर रहते हैं. अमेरिका के एक दौरे पर जाने से पहले यूरोप की अगली यात्रा में अल्लारक्खा और जाकिर के सिर्फ पश्चिम जर्मनी में ही 20 दिनों में 21 कार्यक्रम देने की उम्मीद है. पहले जाकिर के खाते में उनके

अल्लारक्खा कहते हैं, "मुझे पक्का विश्वास है कि जाकिर ने अपनी मां के गर्भ में ही तबले के बोल सुन लिए थे और जान चुका था कि तबला क्या होता है. जब वह बच्चा था तब तबले के बोल मैं उसके कानों में गुनगुनाया करता था"

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अमेरिका स्थित संगीत मंच 'शक्ति' के कई रिकार्डों के अलावा उनके चार एकल रिकार्ड पहले से ही हैं. अपनी अमेरिकी बीवी एंटोनिया और दो बेटियों के साथ जाकिर अब केलिफोर्निया में ही रहते हैं.

अल्लारक्खा पुरस्कारों और रिकार्डों को संतोषदायक और जरूरी भी मानते हैं. लेकिन पूर्ण आत्म संतुष्टि के लिए वे कहते हैं, "वे क्षण महत्वपूर्ण हैं जब आपको लगने लगता है कि किसी तरह आपको विद्या पाने का मौका मिला और अब आप अधिक से अधिक सीखकर मात्र अपना कर्त्तव्य पूरा कर रहे हैं. उसके बाद इस विद्या को चारों तरफ फैला रहे हैं." वे बड़े सरल भाव से कहते हैं, "मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. मेरे अंदर न तो खुद के बारे में और न ही अपनी कला के बारे में कभी संदेह जागा."

अभी दस साल पहले वे जालंधर के मशहूर बाबा हरबल्लभ मेले में प्रतिदिन एक एकल कार्यक्रम दिया करते थे. वे कहते हैं, "तबला बजाते वक्त मुझे हमेशा लगता रहता है मानो मैं मालिक (अल्लाह) की हाजिरी (इबादत) लगा रहा हूं. मैं मन ही मन मालिक से इश्क बनाए रखने की भीख मांगता रहता हूं. मैं इबादत करता हूं कि मालिक, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है और अब मुझे ताकत दे. उस दिन ऐसा हुआ मानो लोग मेरे संगीत के जरिये बाबा से रूबरू हो रहे हों. तबला बजाते हुए मैं अपनेआप में खोया अल्लाह से इबादत कर रहा था कि मेरी रक्षा करो. एकाएक मानो मेरे बाजुओं के बीच हवा का एक तूफानी झोंका उठा और पूरे शामियाने को झकझोरने लगा. शामियाने के खूंटे उखड़ने लगे. श्रोताओं में से कुछ लोग शामियाने को बचाने के उपाय में जुट गए. लेकिन दस सेकेंड के भीतर ही सब कुछ शांत हो गया. आसमान में न तो कहीं कोई बादल का टुकड़ा था और न ही कोई ऐसा चिन्ह् जिससे एकाएक आए इस तूफान के कारण का कोई पता चलता."

जाकिर नया छंद छेड़ते हैं और अल्लारक्खा उसे अनायास उठा लेते हैं, सुधारते हैं और अपने बेटे को वापस उसे उठाने को कहते हैं. जाकिर उसे उठा लेते हैं और दुबारा पिता के लिए छोड़ देते हैं

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पंजाब में आज भी अल्लारक्खा को मानने वाले ढेरों लोग हैं. वहां के पुरद्वारों में गाने और तबला बजाने वाले रागी ढाडी पंजाबी उनके शिष्य हैं. आज भी नामधारी सिख अपने लड़कों को अल्लारक्खा के पास शिक्षा लेने बंबई भेजते हैं. जब वे किसी यात्रा पर नहीं होते या अपने में खोए कोई धुन बनाने में मस्त नहीं रहते तब वे जुहू के शिवाजी पार्क के पास एक पुराने सरकारी मकान के साधारण सजे-धजे कमरे में शागिर्दों को तालीम दिया करते हैं. इस काम में उनके दोनों बेटे 26 वर्षीय फजल और 24 वर्षीय तौफीक उनका हाथ बंटाते हैं. फजल अपने संगीत मंच 'दिव्या' के माध्यम से विदेश यात्राओं पर जाते रहते हैं और तौफीक नाटकों के लिए संगीत तैयार करते हैं.

उनके शागिर्दों में 9 से 20 साल की उम्र के लड़के हैं. वे कमरे में दाखिल करते ही श्रद्धा से अल्लारक्खा के पैर छूते हैं. बड़े प्यार से वे सभी शागिर्दों के तबलों को कसते हैं. तीन नए लड़कों को एक साथ बैठाकर वे शुरू करते हैं. "तुम लोग एक साथ शुरू करो. ठीक है, एक, दो, तीन, चार, धा!" शागिर्द तबले पर उस्ताद की उंगलियों की थिरकन को ध्यान से देखते हैं: "धा धिन धिन धा, ता तिन तिन ता, धाति, धाति धा धा."

"ठीक है, दुबारा करो, एक, दो, तीन, चार: ती दारा दी दा दिना दा के बोल ठीक से निकालने के लिए तबले के इस जगह अपनी उंगलियों से चोट करो." वे एक 14 वर्षीय लड़के की तरफ देखकर कहते हैं, "अपने बोल बदलो. ठीक है ऐसे थाप मारो." वे दिखाते हैं कि एक खास बोल के लिए तर्जनी को कितना ऊपर उठाकर ठीक जगह पर गिराना होगा. इसके बाद थोड़ी तालीम पाए शागिर्दों के एक दल से वे कहते हैं, ध्यान रखो, तुम थाप बढ़ा रहे हो. कभी हौसला न खोओ. अच्छा ठीक है, अब मेरे साथ बजाओ." एक साथ

वे एक-दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को छेड़ते हैं, आपस में खेलते हैं. ज़ाकिर कहते हैं, "मैं जानबूझकर घालमेल करता हूं. उनके सामने बच्चा बनने में बड़ा मजा आता है"

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

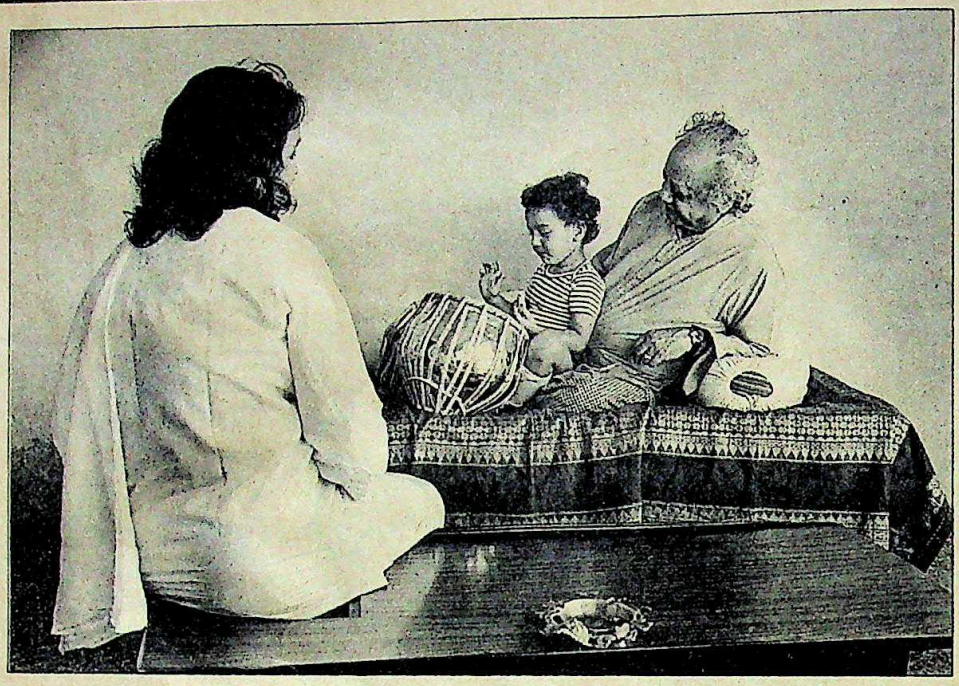

अल्लारक्खा के लिए धार्मिक निष्ठा और कला में फर्क नहीं है. जाकिर कहते हैं, "उनमें एक तरह की सरलता है, एक तरह का अज्ञान भी. उनका कोई दोहरा व्यक्तित्व नहीं है, वे जानते हैं वे कहां जा रहे हैं"

तबले बज उठते हैं और ऐसा लगता है मानो उन्होंने अपने शागिर्दों की थिरकती उंगलियां और तबलों पर पड़ती उनकी थापें अपने दोनों हाथों में भर ली हैं.

जाकिर को याद आता है कि वे हमेशा अपने पिता के वादन से ईर्ष्या किया करते थे. "वे एकदम ठोस और गहरे बोल हमेशा निकाल सकते हैं. मैं उतनी गहराई कभी नहीं पा सका. इसलिए मुझे तकसीन पर ही ध्यान देना पड़ता था. वे जो एक उंगली से कर दिखाते थे वही बोल निकालने में मुझे पूरा हाथ चलाना पड़ता. अगर उन्हें बोल में गहराई लाने के लिए तर्जनी का प्रयोग करना पड़ता तो उसी के लिए मुझे दो उंगलियां चलानी पड़तीं. लेकिन इसी तरह उनसे होड़ में नए बोल निकालने लगा. और अब वे बोल ही मुझे बहुत उत्तेजित कर देते हैं." जाकिर ने सीटल के वाशिंगटन विश्वविद्यालय से अभी-अभी चीनी, अफ्रीकी और इंडोनेशियाई संगीत की पढ़ाई समाप्त की है.

हरिप्रसाद चौरसिया, शिव कुमार शर्मा, भीमसेन जोशी, पंडित जसराज और पंडित रविशंकर के साथ पुणे, मद्रास, बंगलूर, मैसूर, कलकत्ता और अंबाला के अनवरत दौरों से लौटकर जाकिर अपने घर बंबई में बहनों— खुर्शीद और रज़िया, भाइयों और मां के साथ खुशी-खुशी दिन बिताते हैं. वे ऐसे हर पल का आनंद लेते हैं. उनके ऐसे रहने में एक तरह का आत्मविश्वास दिखता है. यह उसी व्यक्ति में मिल सकता है जिसे इतनी ज्यादा प्रसिद्धि पाने के लिए ज्यादा मशक्कत न करनी पड़ी हो. "मैं इसे कोई काम नहीं मानता. मुझे इसमें बड़ा आनंद आता है. इस पेशे में तो मैं यूं ही चला आया. मैंने संगीत सभाओं में जब बजाना शुरू किया तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं इनमें बजा भी सकता हूं. मैं इसके प्रति जागरूकता या इसे जाने-बूझे बगैर ही पूरी निपुणता के साथ बजाने लगा."

सात साल की उम्र में जाकिर ने सार्वजनिक मंच पर सबसे पहले तबला बजाया. और वह भी उस्ताद अली अकबर खां साहब जैसे दिग्गज के साथ. उसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. 17 साल की उम्र में जाकिर अमेरिका चले गए. उनके पिता कहते हैं, "वह समर्थ था. मैंने उसे वहां जाने और विद्या के प्रचार का आशीर्वाद दिया. वह उसी उम्र में एक पूरा कलाकार था." वहां जाकिर अपनी कंपनी शुरू करने से पहले अली अकबर खां द्वारा शुरू किए गए विद्यालय में तबला और संगीत की शिक्षा देते रहे. वे कहते हैं, "लेकिन आज भी मुझे पंडित रविशंकर की सलाह याद है, विदेश जाना तो ठीक ही है पर याद रखो कि तुम्हें अपनी देश में एक शास्त्रीय संगीतज्ञ के रूप में स्वीकृति मिलनी चाहिए. हमेशा अपने जड़ों को सींचते रहना चाहिए."

और पिछले महीने यह स्वीकृति पद्मश्री के रूप में मिली. उनके पिता को यह सम्मान दो दशक पूर्व मिल चुका है. बंबई में जाकिर पंडित रविशंकर के साथ तबला बजा रहे थे. एकाएक आंखों में आंसू भरे अल्लारक्खा ने रविशंकर के कान में कुछ कहा और रविशंकर ने मंच से घोषणा की कि उस्ताद जाकिर हुसैन को पद्मश्री की उपाधि दी गई है. इसके बाद जाकिर उठे और दोनों ही बुजुर्गों के पैर छुए. जाकिर कहते हैं, "मुझे सचमुच बड़ी खुशी हुई क्योंकि इस खबर से मेरे पिता खुश होंगे और उन्हें गर्व होगा."

एक ही ढांचे में ढले दोनों में एक मौलिक अंतर है. अल्लारक्खा के लिए धार्मिक निष्ठा और उनकी कला में कोई अंतर नहीं है लेकिन जाकिर की निष्ठा अपने काम में ज्यादा है. जब कोई कलाकार अपनी कला में ऊंचा उठता है तब कभी उसका साज उस पर हावी रहता है और कभी वह साज पर. "जब मेरे पिता पर उनका साज हावी रहता है, जब वह उनके द्वारा अपना संगीत पैदा करता है, तब उनके चेहरे पर एक तरह की आभा साफ झलकने लगती है. पर साज के हावी होने जैसा कभी महसूस नहीं होता. जब मैं बजाता हूं तब मुझ पर उदासी, भूख, गुस्सा, प्रेम, उन्माद जैसे भाव छाते रहते हैं.

"लेकिन अभी भी उस विशेष अनुभूति की प्राप्ति नहीं हो सकी है. इसे पाने के लिए अभी मुझे और मेहनत करने की जरूरत है. इसके लिए अपने पिता की तरह ही मुझे सब कुछ छोड़कर रियाज में लग जाना होगा. लेकिन मैं नहीं जानता कि ऐसा करने का मुझमें साहस और शक्ति है भी या नहीं. इतना करने के बाद भी मेरे पिता को नहीं मालूम कि उन्होंने क्या पाया है. उनमें एक तरह की सरलता है, एक तरह का अज्ञान भी. मैं उनकी तरह बनने के काबिल भी हो सकूं तो खुशी होगी."

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मीटिंग के दौरान जब मन में उठे चाय की तलब ...

तो डिप लीजिये!

जब आपको झटपट एक कप मनपसन्द चाय की ज़रूरत पड़े, तब ताज महल टी बैग की सुविधा को अपनाइये. न कोई झंझट, न झमेला.

एक कप में एक ताज महल टी बैग रखिये. ताज़ा उबलता पानी डालिये. दो या तीन मिनट तक रखे रहिये. फिर टी बैग निकाल लीजिये. अपने स्वाद के अनुसार दूध और शक्कर मिलाइये. बस, हो गई आपकी चाय तैयार!

कप हो या चायदानी. दोनों में आसानी. (यदि आप चायदानी में चाय बना रहे हैं, तो 4 कप के लिये 3 टी बैग काफी हैं)

ताज महल टी बैग

स्वाद व शान. बनाना आसान!

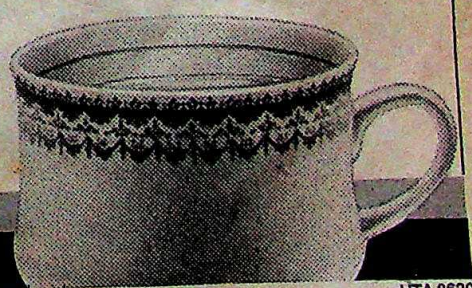

ब्रुक बांड पैकेट चाय.
हर पैकेट में एक-सी, भरोसेमंद क्वालिटी.

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

HTA 8620

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ब्रिटेन

लौट आए नटराज

अमूल्य भारतीय धरोहर रखने वाली ब्रिटिश संस्थाएं चिंतित

नटराज की एक प्राचीन मूर्ति (कीमत: करीब 2.3 करोड़ रुपए) भारत वापस भेजने के ब्रिटिश हाईकोर्ट के फैसले से लंदन स्थित भारतीय नागरिकों में खुशी की लहर दौड़ गई है. पिछले पखवाड़े आए इस फैसले से नटराज मूर्ति प्रकरण की विवादास्पद अदालती लड़ाई का पटाक्षेप हो गया है. ब्रिटिश संग्रहालय की सूचना पर अगस्त '82 में स्कॉटलैंड यार्ड की खुफिया पुलिस ने यह मूर्ति बरामद की.

कनाडा की एक कंपनी बंपर डेवलपमेंट कार्पोरेशन (बीडीसी) ने मूर्ति सुरक्षित रखने के लिए संग्रहालय को भेजी थी. कालगरी स्थित कंपनी के अध्यक्ष, प्रसिद्ध कला संग्राहक व दानी सज्जन राबर्ट बॉर्डेन ने नटराज की मूर्ति 250,000 पौंड (57.5 लाख रुपए) में खरीदी थी. कंपनी के अधिकारियों का कहना था कि उन्होंने इसे लंदन के एक पुरातत्व व्यापारी जूलियन शेरियर से हासिल किया था. जबकि जूलियन का दावा था कि उसके परिवार के पास यह मूर्ति कई सालों से थी.

इस पर भारत सरकार ने यह दावा करते हुए मुकदमा ठोंक दिया कि तमिलनाडु में तंजावुर जिले के पाथुर गांव के अरिल थीरू विश्वनाथ स्वामी मंदिर से 1976 के बसंत में यह मूर्ति चुरा ली गई थी. तमिलनाडु सीआइडी के पुलिस महानिरीक्षक राजशेखर नायर ने जांच के दौरान पाया कि इस मूर्ति को मुसलमान हमलावरों से बचाने के लिए जमीन में गाड़ दिया गया था. बाद में चोरों ने खोदकर इसे मद्रास के व्यापारियों के हाथ बेच दिया. उन्होंने इसे बंबई के किसी व्यापारी को बेचा. इसके बाद मूर्ति कहां गई इसका पता नहीं चला.

झगड़े में फंसी नटराज की यह पंचलौह मूर्ति 100 सेमी. ऊंची और 65 किलो वजनी है. इसे हासिल करने के लिए सरकार ने बीडीसी और लंदन पुलिस दोनों को वादी बनाते हुए मामला दायर किया था. भारत सरकार और तमिलनाडु सरकार ने मशहूर वकील किए और गवाहों तथा विशेषज्ञों को विमान से लंदन ले जाया गया. ब्रिटेन की रानी के वकील एडरियन हेमिल्टन ने यह मामला लड़ा. उनकी सहायता कर रहे थे— बैरिस्टर भास्कर घोरपडे. भारत सरकार की ओर से वकालत लंदन की फर्म जईवाला ऐंड कंपनी ने की.

हेमिल्टन और घोरपडे की जिरह ने कानूनी हलकों में उत्सुकता पैदा कर दी. उनकी दलील थी कि नटराज की चोरी और उसे चुपके से बाहर भेज देने के कारण उस पर से मंदिर का अधिकार खत्म नहीं हो जाता. दोनों ने तर्क दिया कि मंदिर का न्यायिक अस्तित्व भारत में है, उसी तरह नटराज की मूर्ति 'चुरा लेने' के बावजूद उसका न्यायिक अस्तित्व भारत में ही स्थित है.

न्यायाधीश केनेडी का फैसला भी अद्भुत रहा. केनेडी ने कहा कि वे पूरी तरह 'सहमत' हैं कि लंदन में मिली नटराज की यह मूर्ति पाथुर की ही है. फैसले के निचोड़ में बिना किसी लागलपेट के उन्होंने कहा, "नटराज का न्यायिक अस्तित्व प्रतिवादियों से कहीं ऊंचा है."

केनेडी के इस फैसले से भारतीय धरोहर रखने वाली संस्थाओं में खतरे की घंटी बज उठी है. 33,000 भारतीय चित्र, मूर्तिशिल्प और कपड़े पर बुनी कलाएं रखने वाले 'द विक्टोरिया ऐंड अल्बर्ट म्यूजियम' तथा अनगिनत भारतीय धार्मिक वस्तुएं रखने वाले ब्रिटिश संग्रहालय की निगाहें इस मामले पर थीं. असल में 'दि विक्टोरिया ऐंड अल्बर्ट म्यूजियम' ने बहुमूल्य भारतीय वस्तुएं गोदाम में भर रखी हैं और ये धरोहर जनता को दिखाई नहीं जातीं. ब्रिटिश अदालत के फैसले से बाकी बहुमूल्य धरोहरों को वापस पाने का रास्ता ही नहीं खुल गया है बल्कि इससे भारत के लावारिस पड़े मंदिरों से पुरावशेषों और मूर्तियों की तस्करी रोकने की अहमियत भी जाहिर हुई है.

—रमेश बत्रा

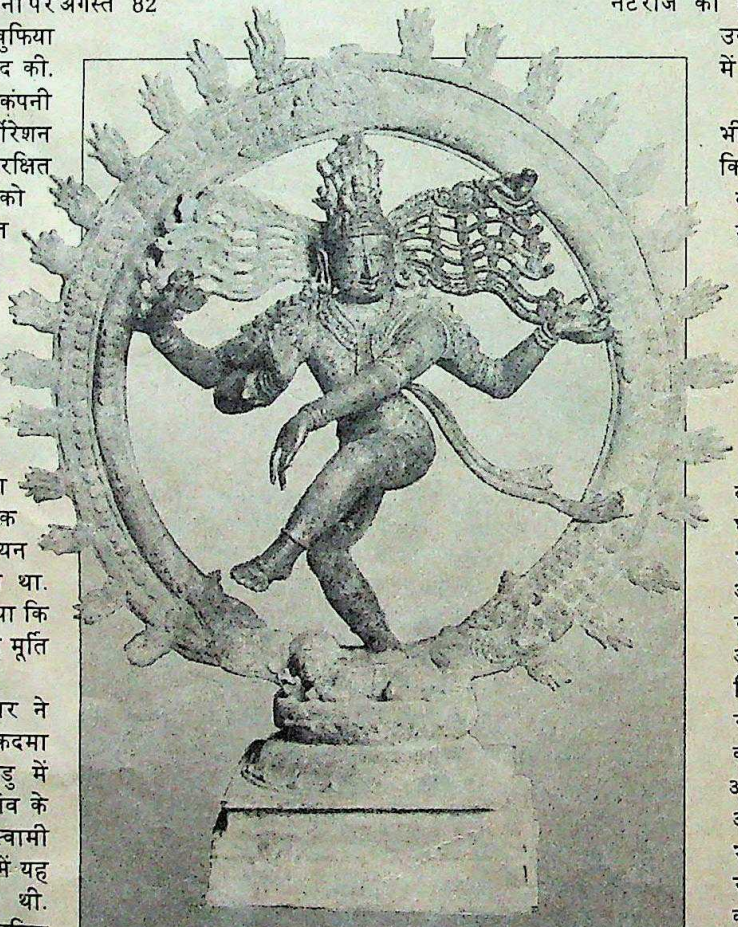

नटराज की चुराई गई मूर्ति को वापस भारत भेजने के ब्रिटिश अदालत के फैसले से बाकी अमूल्य धरोहरों को वापस पाने का रास्ता खुल गया है

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

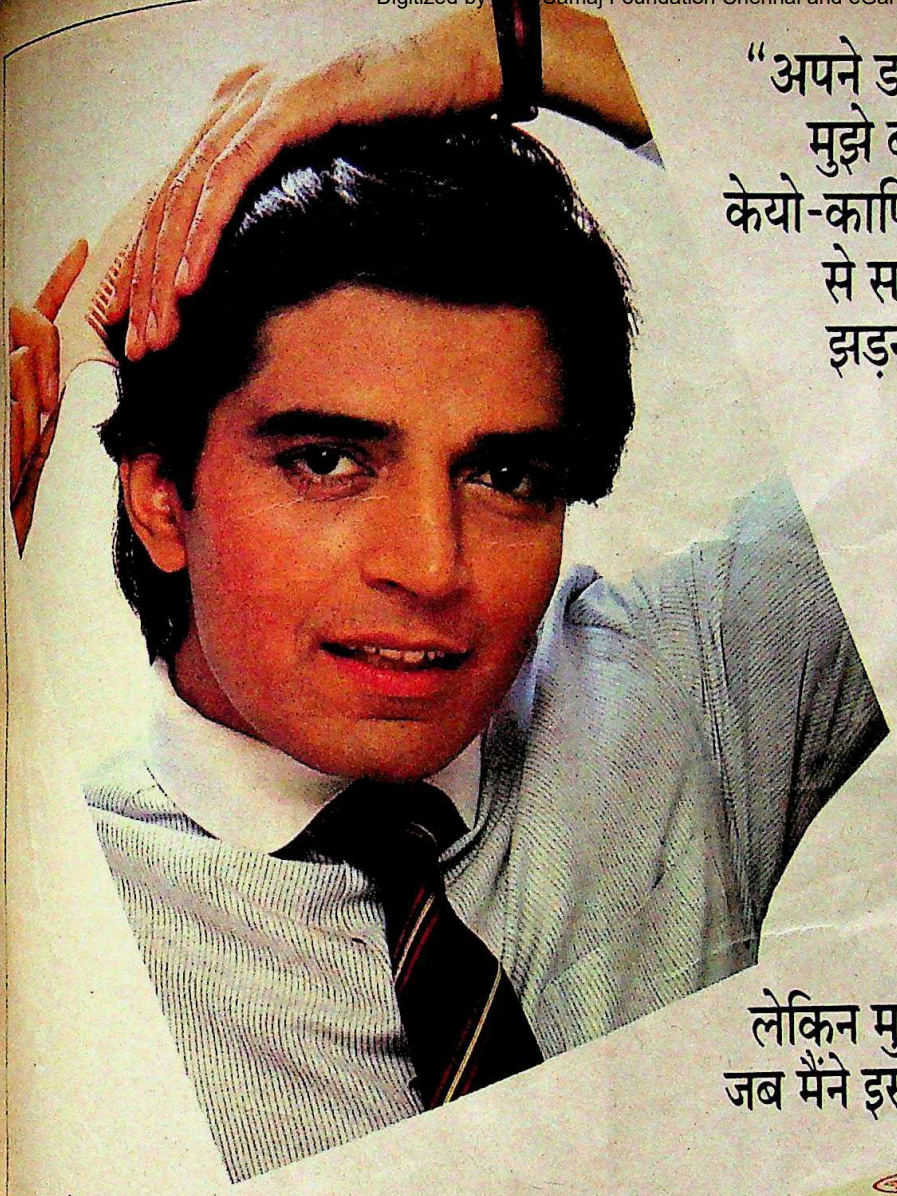

"अपने डॉक्टर से यह जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि केयो-कार्पिन हेयर वाइटालाइज़र से सचमुच बालों का झड़ना रुक जाता है।

लेकिन मुझे विश्वास तब हुआ जब मैंने इसका इस्तेमाल किया।"

"मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया कि केयो-कार्पिन हेयर वाइटालाइज़र*, व्यापक गवेषणा पर आधारित एक अपूर्व वैज्ञानिक फार्मूले से बना है। उन्होंने यह भी बताया कि यह बालों की जड़ों को मज़बूत करनेवाले सभी आवश्यक प्रोटीन तत्व, को-एन्ज़ाइम और विटामिन भी उपलब्ध करता है।

मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि इसने मेरे बालों का झड़ना निश्चितरूप से रोक दिया है और साथ ही रूसी भी खत्म हो गई है।"

देखिए, गवेषणा-रिपोर्ट से उद्धृत एक अंश:

"सभी मामलों में रूसी के सम्पूर्ण खात्मे के साथ ६६.६६% मामलों में शानदार एवं ३३.३३%में बढ़िया नतीजा हासिल हुआ और बालों का झड़ना तो लगभग शत प्रतिशत रुक गया...इसलिए, यह कहा जा सकता है कि केयो-कार्पिन हेयर वाइटालाइज़र की सफलता-दर शत प्रतिशत है।"

इंडियन मेडिकल गज़ट ११८ २२३ (१९८४)

बालों का झड़ना रोकने का प्रमाणित वैज्ञानिक तरीका।

Dey's® दे'ज मेडिकल की संभाल, आपका भरोसा।

*यह शृंगार सामग्री नहीं है।

DMHV-4

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हमारे रहते आप उत्तर प्रदेश में कहीं भी बेघर नहीं हैं

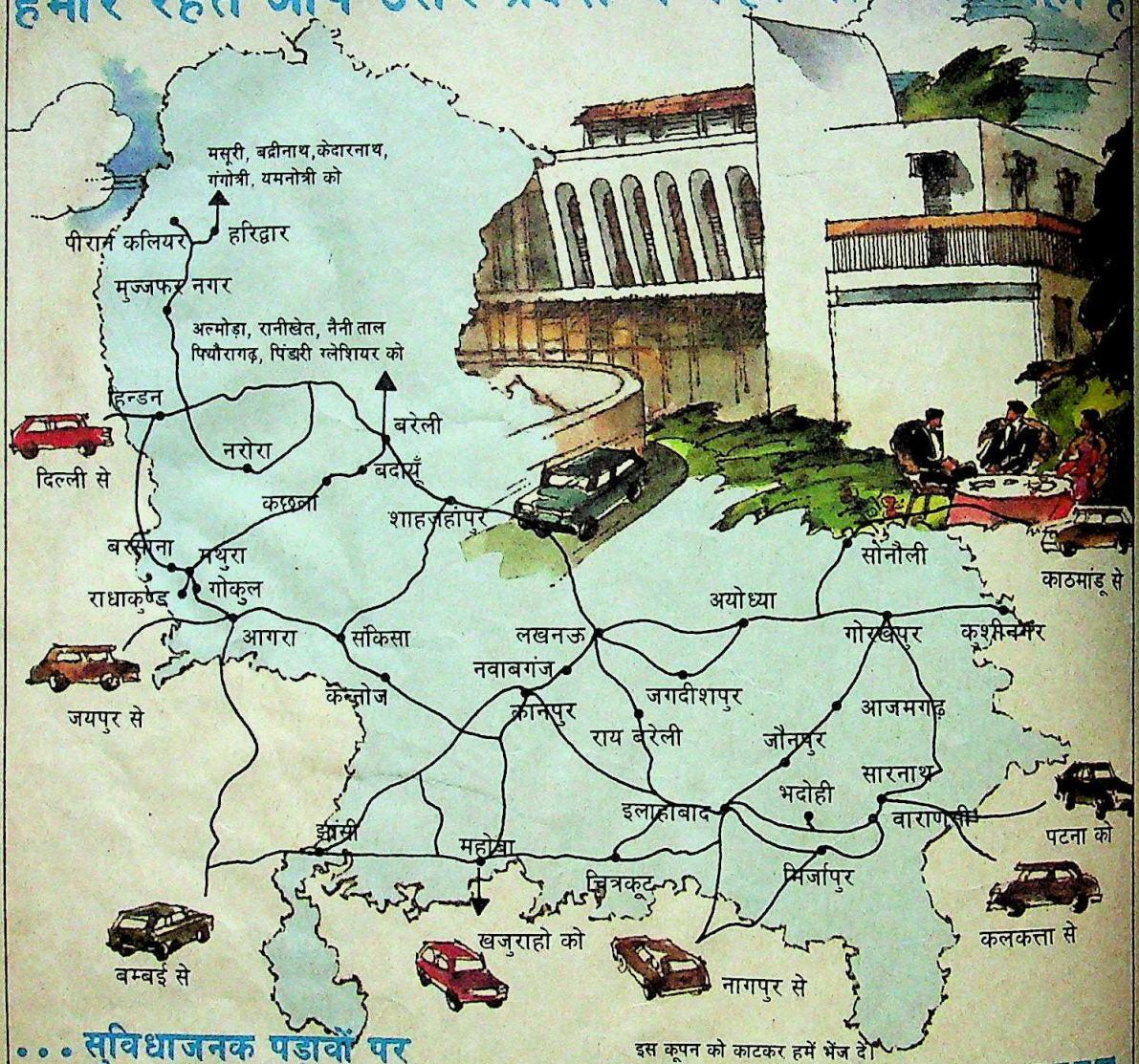

...सुविधाजनक पड़ावों पर 35 विश्राम गृहों में आपको अपने घर सा अपनापन मिलेगा।

उत्तर या दक्षिण, पूर्व या पश्चिम जिधर भी जाना चाहें यात्रा पर निकल पड़िये। घूमते-टहलते यदि थकान महसूस हो तो उत्तर प्रदेश पर्यटन के विश्राम गृहों पर पड़ाव डालिए। राह में सुविधाजनक 35 स्थलों पर निर्मित ये विश्राम गृह यात्रा की थकान को मिटाने के लिये बहुत ही आरामदायक वातावरण प्रदान करते हैं। ठहरने, नहाने-धोने, खाने-पीने की पूर्ण व्यवस्था से सुसज्जित उपयोगी विश्रामस्थल जहाँ उत्तर प्रदेश की आतिथ्य परम्परा आपको सुखद एवं निजीपन की अनुभूति देगी।

- आगरा • अयोध्या • इलाहाबाद • कछला • कन्नोज
- कुशीनगर • गोकुल • गोरखपुर • चित्रकूट
- जगदीशपुर • झाँसी • नरोरा • नवाबगंज
- पीरान कलियर • बदायूँ • बरसाना • बरेली • भदोही
- मिर्जापुर • मुजफ्फरनगर • मथुरा • महोबा
- राधाकुण्ड • राय बरेली • लखनऊ • वाराणसी
- शाहजहांपुर • संकिसा • सोनौली • सारनाथ
- हरिद्वार • हिन्डन

उत्तर प्रदेश में हर जगह जहाँ आप ठहरना चाहें।

इस कूपन को काटकर हमें भेज दें।

कृपया अपने आवास गृहों से सम्बधित सम्पूर्ण जानकारी दें

नाम .....

पता: .....

इच्छित भाषा: अंग्रेजी/हिन्दी

उत्तर प्रदेश पर्यटन

चित्रहार भवन 3-नवल किशोर मार्ग,
लखनऊ-226001 उ. प्र.
फोन: 48349, 45252, 47749

• तत्कालिक आरक्षण केन्द्र चन्द्रलोक भवन,
36, जनपथ, नई दिल्ली-110001 फोन: 322251.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

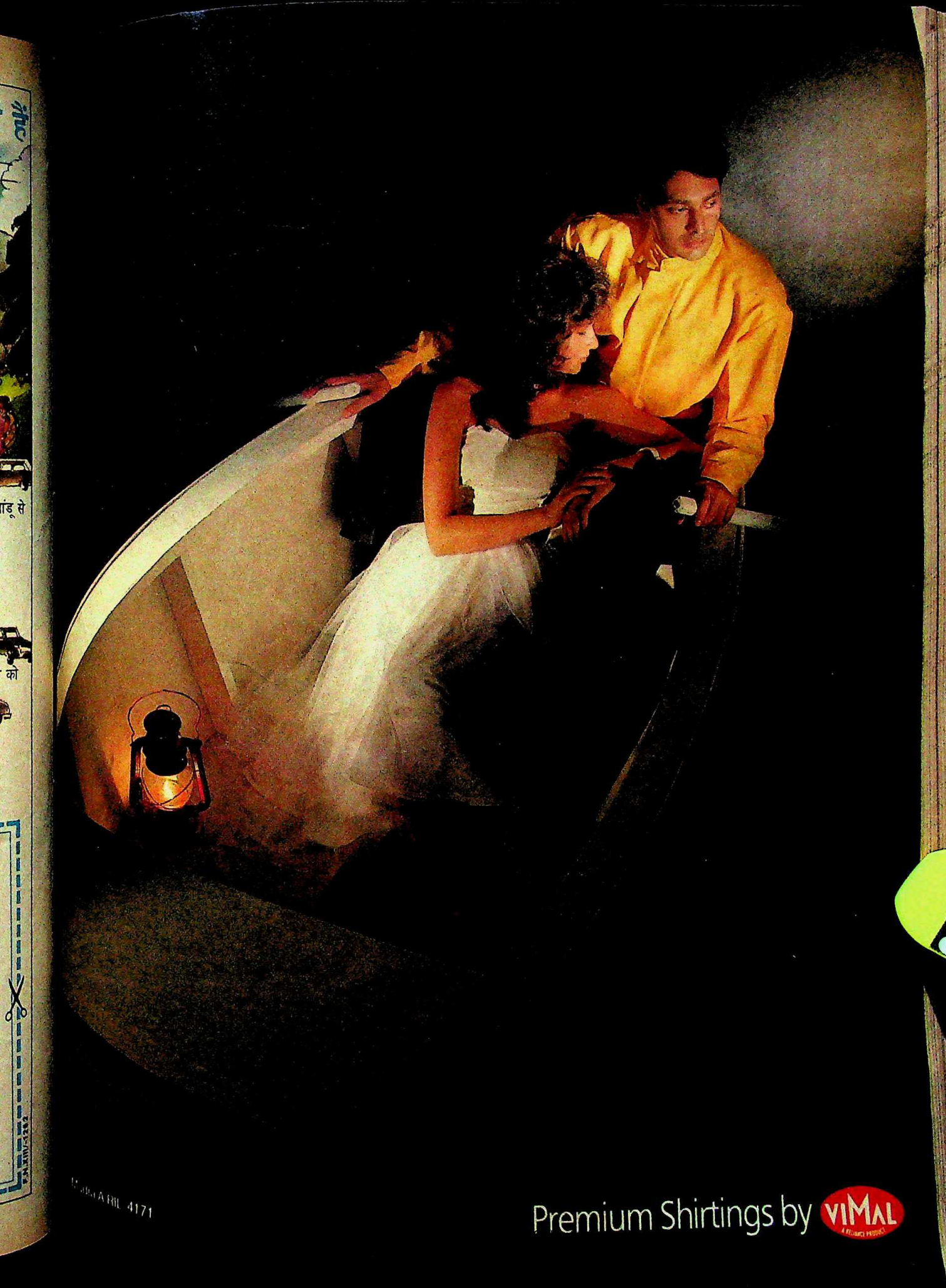
Premium Shirtings by
VIMAL

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वेरका

देसी घी

100% शुद्ध

वेरका देसी घी। स्वाद, शुद्धता व उत्तमता में लाजवाब। वेरका के बिना आपका भोजन अधूरा है।

मिल्कफ़ैड का एक उत्तम उत्पादन

MILKFED

दी पंजाब स्टेट कोआप्रेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्ज़ फेडरेशन लिमिटेड, एस० सी० ओ० न० 3015-16 सैक्टर 22-डी, चण्डीगढ़ - 160 022

OPERATION FLOOD

UNION-2288

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सभी फोटो: प्रमोद पुष्करणा

चंपानेर

तिल-तिल घुलती विरासत

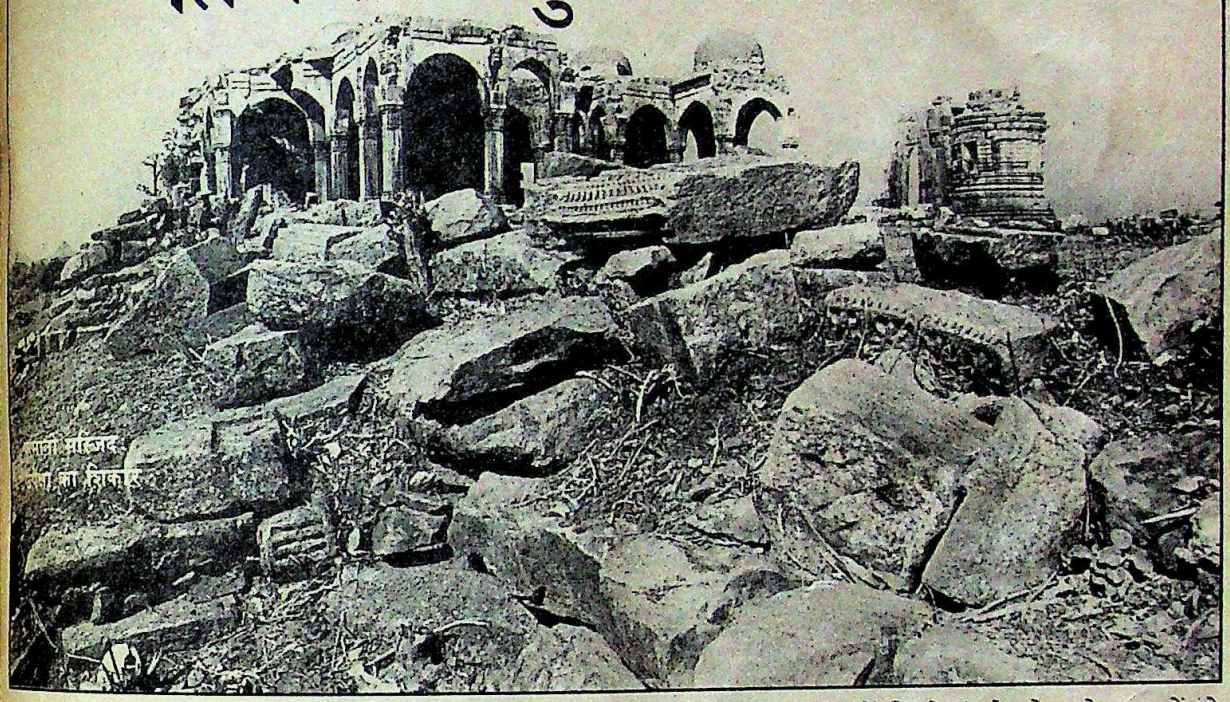

एक जमाने में लोग यहां के आलीशान भवनों, विशालकाय मस्जिदों और पत्थर की महीन नक्काशी को हैरत से देखा करते थे, लेकिन चंपानेर के सौंदर्य को सराहने वाले अब इक्का-दुक्का लोग ही हैं. यों तो हजारों की तादाद में लोग पावगढ़ की पहाड़ी पर बने कालिका मंदिर में दर्शनों के लिए आते हैं, लेकिन यहां के निवासियों (जनसंख्या 2000) और भारतीय पुरातत्व सर्वे (एएसआइ) के बीसेक कर्मचारियों के अलावा मध्य युग के इन वैभवशाली खंडहरों की ओर शायद ही किसी का ध्यान जाता हो.

एक अनुमान के अनुसार इन्हें सातवीं शताब्दी में राजपूतों ने बनवाया था. पंचमहल जिले में वडोदरा से पचास किलोमीटर पूर्व में स्थित चंपानेर को 1484 में गुजरात के सुल्तान महमूद बेगरा ने जीत कर अपनी राजधानी बनाया. सुल्तान ने इसे नए सिरे से संवारना शुरू किया. नए भवन तैयार किए गए, ऊंची मस्जिदें खड़ी की गईं, नई सड़कें, पुल और तालाब बनवाए गए. सौंदर्य बगीचे लगवाए गए. लेकिन सुल्तान के पतन के साथ ही चंपानेर के भाग्य का सूरज भी अस्त हो गया.

लेकिन यह ह्रास कहां तक हुआ, इसका निर्णय हाल ही में वडोदरा की एक स्वैच्छिक संस्था 'हेरिटेज ट्रस्ट' के प्रयत्नों से आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला में ही हो पाया है. 'भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर न्यास' और एएसआइ द्वारा प्रायोजित इस कार्यशाला में कई वास्तुविदों और पुरातत्वविदों ने भाग लिया. इनमें रोम में स्थित 'अंतरराष्ट्रीय संरक्षण केंद्र' के निदेशक सर बर्नार्ड फील्डेन भी थे, जिन्होंने चंपानेर को यूरोप के पोम्पई के खंडहरों के समान 'रोचक' बताया.

पुरातत्व विभाग अब ढाई किलोमीटर क्षेत्र में बिखरे चंपानेर के ढहते स्मारकों को बचाने के लिए एक रिपोर्ट तैयार करने की योजना बना रहा है. इन अवशेषों के 61 भवनों में से केवल 38 भवनों को—जिनमें से 20 मस्जिदें भी हैं— पुरातत्व विभाग संरक्षण देता है. बाकी सब उपेक्षित ही हैं. इनमें एक रानी महल और एक चर्चनुमा बिल्डिंग भी है. संभवतः इसे सुल्तान द्वारा लाए गए पुर्तगाली कैदियों ने बनाया था. ये दोनों ही भवन लगभग खंडहर बन चुके हैं.

साठ के दशक के अंतिम वर्षों में उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी और कर्नाटक में हांपी के खंडहरों के साथ-साथ चंपानेर को

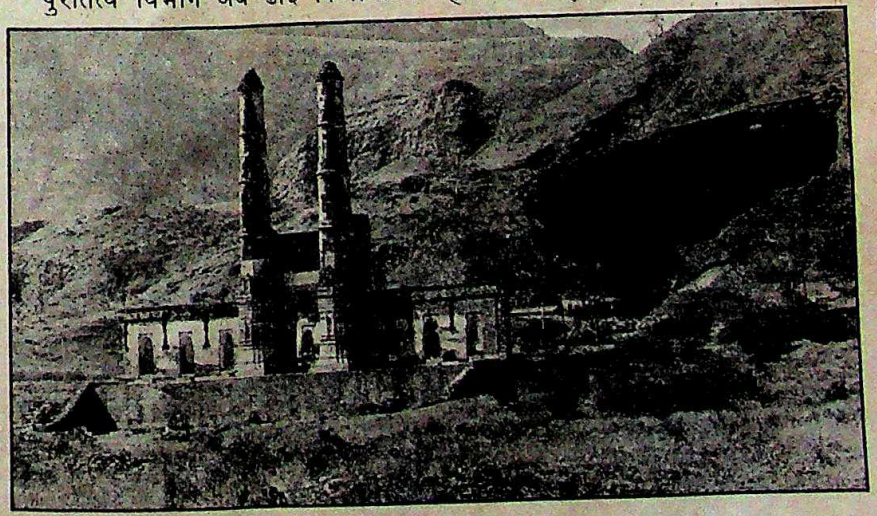

हाथी मस्जिद और (पीछे) पत्थर खदानः सिर पर मंडराता खतरा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भी राष्ट्रीय संरक्षण परियोजना में शामिल किया गया था. इस परियोजना के दो उद्देश्य थे— इन भवनों की संरचना की जानकारी हासिल करना और इनके संरक्षण के लिए नए सुझाव देना. फतेहपुर सीकरी और हांपी में आज भी बदस्तूर काम चल रहा है, लेकिन चंपानेर में सत्तर के दशक में ही रोक दिया गया. वैसे डॉ. आर.एन. मेहता की अगुआई में महाराजा सायाजीराव विश्व-विद्यालय के विशेषज्ञों ने खुदाई का काम पांच वर्षों तक जारी रखा. इस खुदाई के दौरान प्राप्त भवनों में 'अमीर की मंजिल' मुख्य है जिसमें एक अस्तबल, रिहायशी मकान और कई प्रहरी कक्ष हैं. इसके

पुरातत्व विभाग ने चंपानेर की ढहती धरोहर को बचाने का अनमना प्रयास भर ही किया है

अलावा एक व्यावसायिक सस्थान भी है जिसे शायद दुकानदार इस्तेमाल करते होंगे.

चंपानेर परियोजना के स्थगन के कारण तो स्पष्ट नहीं हैं लेकिन एक मत के अनुसार एएसआइ के पुरातत्व विशेषज्ञों और विश्वविद्यालय के आपसी झगड़े के कारण ऐसा हुआ. इसके अलावा राज्य के पुरातत्व विभाग ने भी इसमें विशेष दिल-चस्पी नहीं ली. फिर दो-एक और कारणों से भी चंपानेर पिछड़ गया. फतेहपुर सीकरी को इसलिए प्राथमिकता दी गई कि यह पर्यटन मार्ग पर पड़ता था और हांपी को उचित राजनैतिक समर्थन मिलता रहा. चंपानेर में ऐसी एक भी खूबी नहीं थी. फिर एएसआइ ने भी आधे दिल से काम किया. हालांकि थोड़े-थोड़े अंतराल के बाद प्रमुख स्मारकों की मरम्मत होती रही, पर कुल मिलाकर सरकारी रवैया आलस और उदासीनता का ही रहा. (उदाहरण के तौर पर हाल तक चंपानेर पर अंग्रेजी की एक भी पुस्तिका उपलब्ध नहीं थी). सबसे बढ़कर इन खंडहरों के विस्तार को देखते हुए स्टाफ बहुत कम है. कमानी मस्जिद तो सरकारी लापरवाही का सजीव उदाहरण है. आधी से ज्यादा मस्जिद पत्थरों का ढूह भर है.

हैरानी की बात नहीं कि ज्यादातर स्थानीय लोग भी चंपानेर के महत्व से अपरिचित हैं. हां, कुछ लोगों ने सुल्तान के 'छिपे खजाने की खोज' में कई जगह खुदाई जरूर कर डाली है. पिछले साल ही इतारी मस्जिद और 'अमीर की मंजिल' के फर्शों की खुदाई की गई. शरारती लोगों ने एक मंडप के बीचोंबीच लगे पत्थर तक को खोद डाला. इसकी सुरक्षा के लिए बनाए गए

खुदाई के बाद मिली अमीर की मंजिल: कोई सुध नहीं लेता

कांटेदार बाड़ और लोहे के दरवाजे शायद ही कभी सलामत रहते हैं.

मध्ययुग के इस शहर को सबसे बड़ा खतरा चंपानेर के आसपास पत्थर की 71 खदानों से हो रहा है. उनमें दिन में दो या तीन बार विस्फोट किया जाता है जिससे इन स्मारकों की नींवें कमजोर पड़ जाती हैं. कइयों में तो दरारें भी साफ नजर आने लगी हैं. पश्चिमी क्षेत्र के पुरातत्व अधीक्षक एस.बी. वाहल पेंसिल के आकार की ऊंची-ऊंची मीनारों को पहुंचे नुकसान से विशेष रूप से क्षुब्ध हैं. "कोई नहीं जानता कि इन्हें कितना नुकसान पहुंचा है. पर एक बात तय है यदि इनमें से एक मीनार भी गिर गई तो बाकियों को बचाए रखना मुश्किल हो जाएगा." हालांकि खदान मालिकों के लाइसेंसों की अवधि समाप्त होने के कारण खुदाई अब अपने आप गैरकानूनी हो चुकी है पर खनन का काम अभी भी जारी है.

इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि अब चंपानेर से सात किलोमीटर दूर रंजीतनगर में एक रसायन फैक्टरी की योजना बनाई जा रही है. आशंका इस बात की है कि इससे निकलने वाले रासायनिक पदार्थों से इन प्राचीन धरोहरों को नुकसान होगा. वाहल चेतावनी देते हैं, "इससे इमारतों के पिलछौहें पत्थरों का रंग काला या हरा पड़ जाएगा."

अधिकारियों की ऐसी अज्ञानता और लापरवाही के ढेरों उदाहरण हैं. सबसे शोचनीय उदाहरण वन विभाग का है, जो दीवार बनाने के लिए खंडहरों के पत्थरों का इस्तेमाल कर रहा है. क्षुब्ध एएसआइ के कई टेलीग्राम भी विभाग को सही रास्ते पर लाने में असमर्थ रहे हैं. इसके अलावा एक समस्या और भी है. चंपानेर के निकट शिवराजपुर को जाने वाली एक छोटी लाइन की रेलगाड़ी कई असंरक्षित स्मारकों के बीच से ही होकर गुजरती है.

धरोहर न्यास के हाथ में अब चंपानेर को बचाए रखने का दुरूह कार्य है. एक तरफ तो इसके अध्यक्ष हंसमुख शाह पहले ही राज्य उद्योग विभाग को लिख चुके हैं कि दो वर्ष के भीतर-भीतर चंपानेर से दो किलोमीटर की दूरी तक खनन का काम बंद हो जाना चाहिए. न्यास नए खुलने वाले कारखानों को भी तुरंत बंद करवा देने के पक्ष में है. दूसरी ओर न्यास अधिकारियों पर दबाव डालने की योजना बना रहा है कि चंपानेर को वन संरक्षण कानून के अंतर्गत 'प्राकृतिक शिक्षा अभयारण्य' घोषित किया जाए. इससे यहां की जमीन के उपयों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन पूर्णतः निषिद्ध हो जाएगा. ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं ने चंपानेर के निवासियों से भी इन खंडहरों की सुरक्षा के लिए सहायता मांगना शुरू कर दिया है.

लेकिन ट्रस्ट को पहले खदान के मालिकों को समझाना पड़ेगा, जिन्होंने राजनीतिकों की सहायता लेने के प्रयास शुरू कर दिए हैं. न्यास के सचिव करन ग्रोवर कहते हैं, "हम केवल एक दबाव गुट के रूप में ही काम कर सकते हैं और थोड़ा-बहुत कर भी रहे हैं. बाकी निर्णय सरकार के हाथ में है." अधिकारियों के रिकार्ड को देखते हैं तो लगता नहीं कि सरकार का जल्दी ही कुछ करने का इरादा है. —उदय माहूरकर, चंपानेर से

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सुरीला संगीत कानों में गूंजे... तो आप भी झूमे गा उठे!

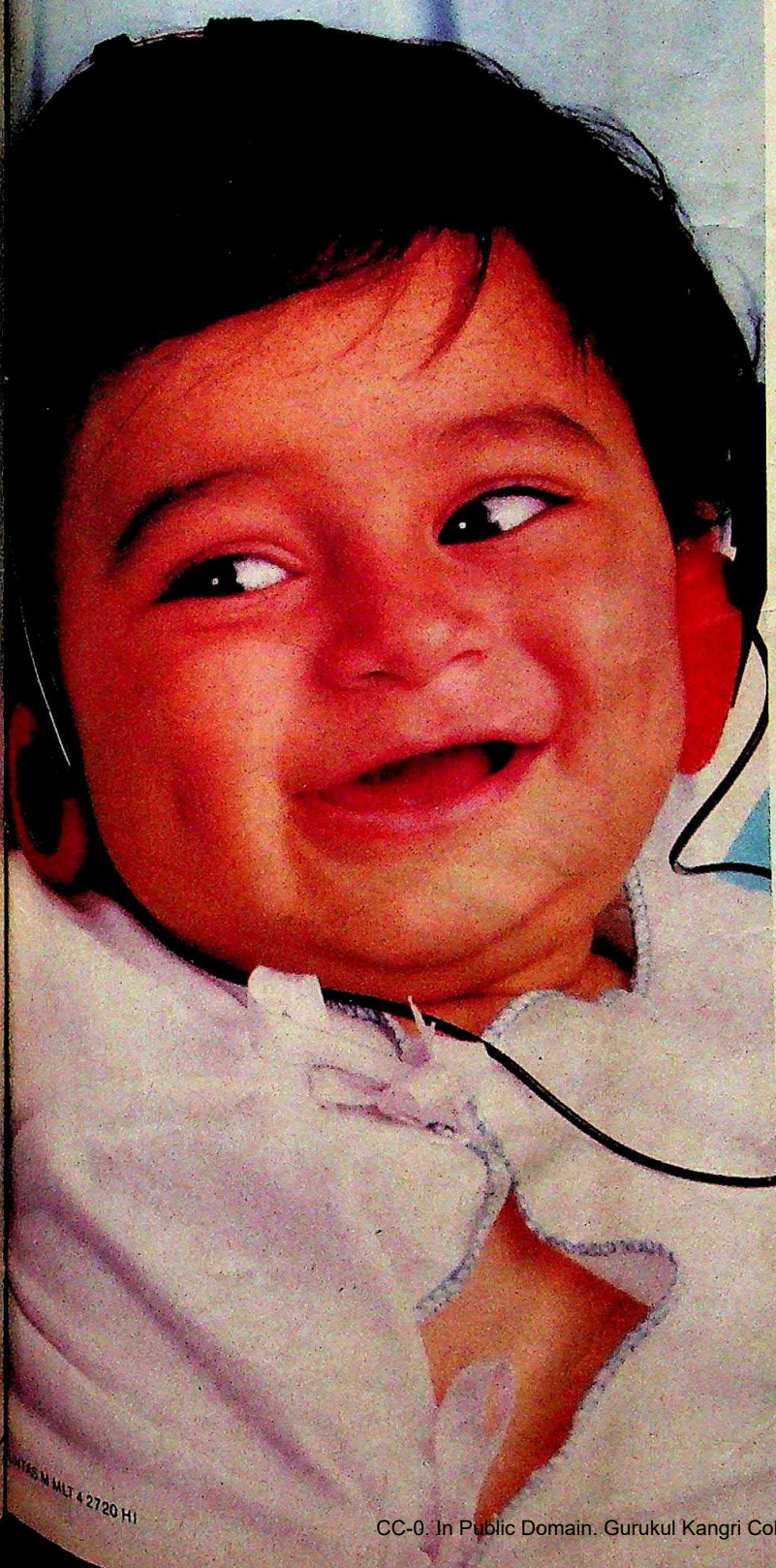

नये

मैलट्रैक

कैसेट

आवाज़ में फूंके जान.

आखिरकार आपके लिए आ ही गई ऐसी भारतीय टेप जो जापानी टेप से ले टक्कर.

मैलट्रैक कैसेट का रैपर खोलते ही एक ख़ास एहसास होता है और बजाते ही आवाज़ का जादू आपको घेर लेता है.

मैलट्रैक का ये सुरीला करिश्मा उत्कृष्ट जापानी टेक्नीक की देन है.

- धूल रहित वातावरण में निर्मित होने के कारण इन कैसेटों में होती है आवाज़ और संगीत की हू बहू रिकार्डिंग और रीप्रोडक्शन क्षमता.
- टेप पर एक समान रूप से फैले मैग्नेटिक कणों के कारण मिले आवाज़ में सही-सटीक क्वालिटी.
- हाय टेन्साइल पॉलीएस्टर फिल्म जो न खिंचे न टूटे.
- खास पदार्थ से चिपके होने के कारण मैग्नेटिक कण न तो टेप से उखड़ते हैं, न ही रिकार्डिंग मशीन को नुकसान पहुंचाते हैं.
- इसके आवरण और पुर्ज़े अचूकता से तैयार किए जाते हैं इसलिए घर्षण भी कम से कम और टेप फँसने – रुकने का डर भी नहीं.
- निर्माण के दौरान हर पहलू से क्वालिटी की लगातार सही देख-रेख के कारण आप पाते हैं हर तरह से एक उत्कृष्ट उत्पादन.

ये सब कुछ बिल्कुल मुनासिब दामों पर आपके लिए आसानी से उपलब्ध है फैला हुआ डीलरों के पास.

तो अब देर किस बात की! अपने मनपसंद गीतों को नये मैलट्रैक कैसेट पर रिकार्ड कीजिए और जीते-जागते संगीत का आनंद उठाइए!

जापानी टेक्नॉलॉजी द्वारा निर्मित

MURUGAPPA
ELECTRONICS LTD.

मुरुगप्पा इलेक्ट्रॉनिक्स लि.
पैरी हाउस, तीसरी मंजिल
४३ मूर स्ट्रीट, मद्रास ६०० ००१

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

हॉलिडे से कहीं ज्यादा रोमांचक... 'हिलिडे'!

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

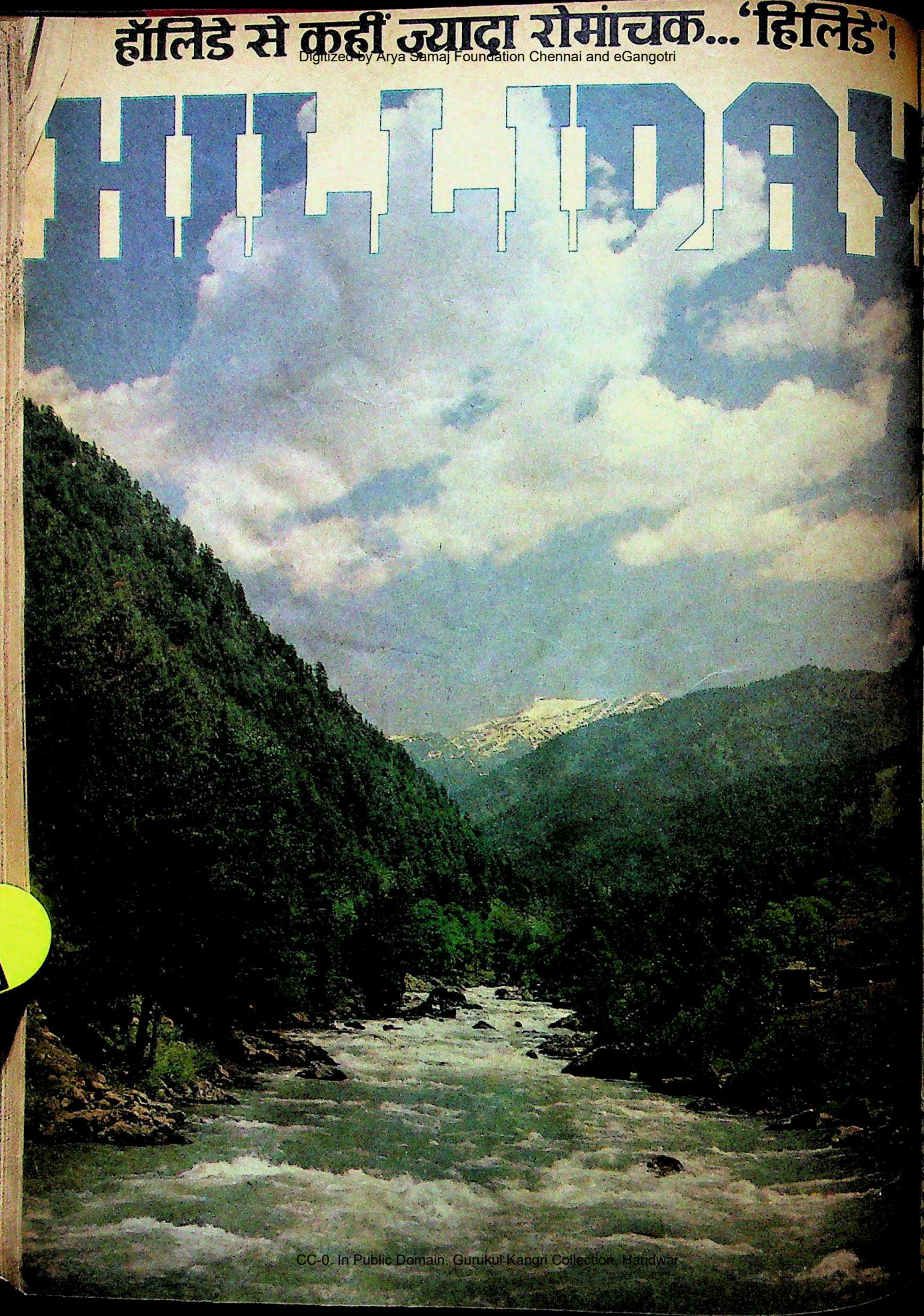

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इस पखव

...ति की बाहों में आमंत्रण-स्वास्थ्य और आनंद भरे क्षण

...से आती ठंडी, सुहानी हवा. पेड़-पत्तों से छन-छन कर गुज़रती...
...की खुशबू चुराती. आपको
...से सराबोर करती. वर्षभर—
...भी समय... हर समय !
...डे' का यही है अनोखा आनंद!
...सुखद. बेहद ताज़गी भरा.
...कर देने वाला.
...यह आपको ले चले धरती से
...की ओर !

खुशियों भरी नई राहों पर रखिए क़दम

सुबह की सैर पर निकलिए. प्रकृति के अद्भुत खजाने पर से पर्दा हटाते हुए सूरज को देखिए. जंगली फूल चुनिए. शीतल, साफ झरनों संग खेलिए. घुड़सवारी कीजिए. मछलियाँ पकड़िए. या पर्वतों के बीच सरसराती हवा का गूंजता संगीत सुनिए.
किसी मुस्कराहट का राज़ बन जाइए.
'हिलिडे' है आपके लिए कुछ मनचाहा करने का अवसर !

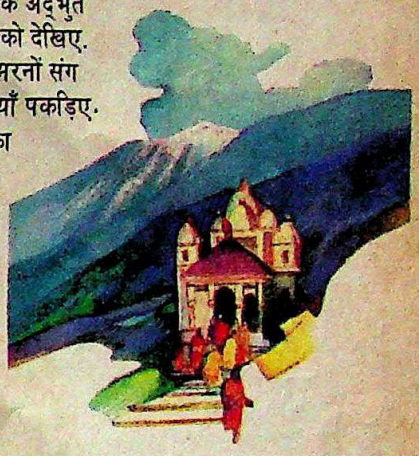

...लों की गोद में आइए

...फुरसत भरे सुहाने पलों में खो जाइए!
यह एक खुला आमंत्रण है सभी पर्वतीय भ्रमण स्थलों से. अनूठी विभिन्नता. दृश्यावली में. जन जीवन में. रंगों और छटाओं में !
अगर आपने कोई एक स्थल देखा भी तो क्या देखा. क्योंकि हर एक का है अपना विशेष आकर्षण —सम्मोहन... और शांतिदायक, निश्चल वातावरण. जी हाँ! 'हिलिड़े' है आराम और फुरसत का नया अंदाज़!

ऊंचाइयों की चुनौती स्वीकारिए

अनजाने इलाकों की पैदल सैर कीजिए.
बर्फीली ढलानों पर स्कीइंग के मज़े लीजिए.
अगर चाहें तो मचलती नदियों की लहरों पर बेड़ा लेकर निकल जाइए.
स्वच्छंद प्रकृति से कीजिए आमना-सामना.
'हिलिडे' पर अद्भुत रोमांच का अनुभव कीजिए.
जल्दी आइए!
पर्वत आपकी प्रतीक्षा में हैं!

कोई भी समय हिलिडे का सही समय

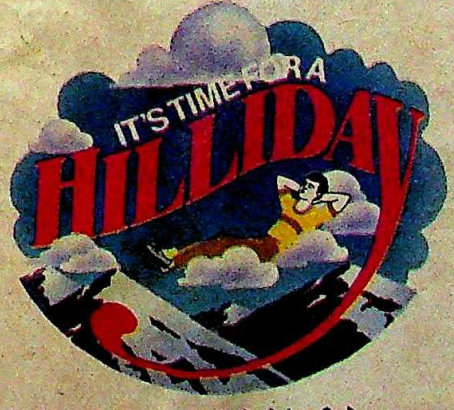

अपना 'हिलिडे' चुनिये

...कौसानी, केदारनाथ, ...कुल्लू, गंगोत्री, गुलमर्ग, ...जोशीमठ, डाछीगाम, ...धनोल्टी, धर्मशाला, ...नारकंडा, पहलगाम, ...मनाली, मसूरी, मंडी, यमुनोत्री, रानीखेत, लद्दाख, लाहौल, लेह, शिमला, स्पीती, श्रीनगर...

दक्षिण
ऊटी, कुन्नूर, कुर्ग, कोटागिरि, कोडाइकनाल, पोनमुढ़ी, येरकाड...

पूर्व
आइज़ॉल, कलिमपोंग, कुर्सियांग, कोहिमा, गंगटोक, दार्जिलिंग, शिलांग...

पश्चिम
खंडाला, पचमढ़ी, पंचगनी, महाबलेश्वर, माउण्ट आबू, लोनावला, सपूतारा...

... और बहुत से अन्य स्थल...
आप स्वयं खोजिए.

पर्यटन मंत्रालय
भारत सरकार

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

MILESTONES/MOT/131a Hn

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नामस भोजानी

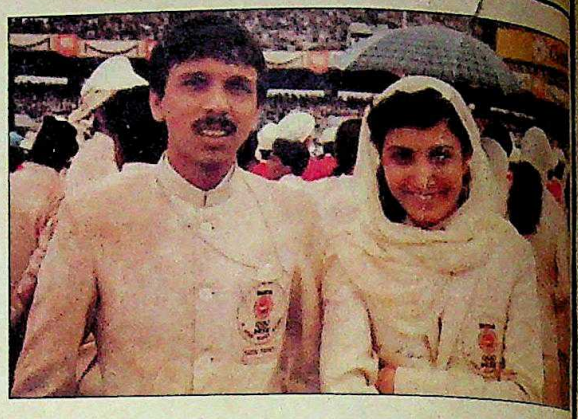

• धधे में उतरने की स्वर्ण जयंती के मौके पर 'ब्लिट्ज़' के मालिक-संपादक **आर.के. करंजिया** (75) के अभिनंदनों का दौर खुद उन्हें भी चौंका गया. लगभग हतप्रभ अंदाज में उनकी प्रतिक्रिया थी, "मैं असमंजस में हूं कि यह सब सच है या माया?" बंबई के बड़े-बड़े लोग उनका दनादन अभिनंदन करने लगे. पहले इंका नेता मुरली देवड़ा ने भारतीय नौसेना के जहाज जवाहर पर उनका अभिनंदन किया और फिर शरद पवार के नेतृत्व में एक नागरिक समिति ने. बात यहीं नहीं थमी. पिछले पखवाड़े ऐसे ही एक समारोह में राष्ट्रपति आर. वेंकटरामन के अलावा शंकरराव चव्हाण, नारायणदत्त तिवारी, अटलबिहारी वाजपेयी, ननी पालकीवाला, राजकपूर और बाल ठाकरे भी मौजूद थे.

• जाज़ टैप-डांसर **सारा पेत्रोनियो** (44) के लिए यह सचमुच घर वापसी जैसा था. पिछले पखवाड़े वे 'जाज़ यात्रा-88' के सिलसिले में दिल्ली में थीं. एक ब्रिटिश-जोर्डन जोड़ी के घर जन्मीं सारा का बचपन बंबई में बीता और अपनी पैरिस टैप डांस कंपनी स्थापित करने से पहले उन्होंने न्यूयार्क में टैप-डांस का प्रशिक्षण लिया. वे कहती हैं, "जब मैंने भारत छोड़ा तभी मैंने कहा था कि मैं वापस आऊंगी. और देखिए मैं यहां मौजूद हूं." और सचमुच सारा ने थिरकते कदमों के साथ दिल्ली के नृत्य प्रेमियों को मोह लिया. वे कहती हैं, "भले ही अमेरिका और फ्रांस ने मुझे डांसर बनाया हो पर एक इंसान के नाते मुझे

पेत्रोनियो: घर वापसी

करंजिया: अभिनंदनों का दौर

भारत ने ही निखारा है. मेरे लिए यह अत्यंत भावुकता भरी घर वापसी है."

• क्रिकेट को शरीफ लोगों का खेल कहा जाता है पर **मनोज प्रभाकर** और **मनिंदर सिंह** के बीच जो कुछ हुआ वह शराफत नहीं था. मौका था सेल ट्राफी का फाइनल जिसमें प्रभाकर ने बैंकिंग स्पोर्ट्स बोर्ड

नामस भोजानी

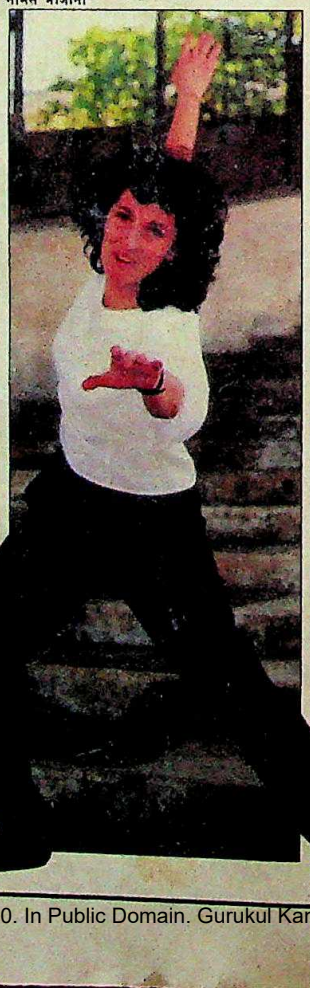

की तरफ से खेलते हुए मनिंदर की एक गेंद पर छक्का जमा दिया. लेकिन अगली ही गेंद पर वे कैच कर लिए गए. इस पर मनिंदर ने दबी जुबान में जो ताना कसा उसके

प्रदीप मांधानी

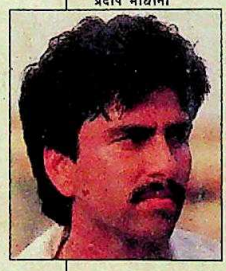

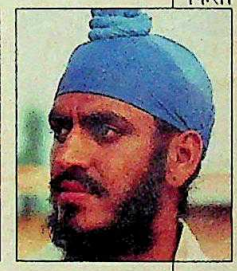

प्रभाकर और मनिंदर

जवाब में प्रभाकर ने उनकी बांह पर बैट जमा दिया. मनिंदर का कहना था, "यह सब अचानक बदमिजाजी में ही हो गया." और उधर प्रभाकर गुस्सा थूकते हुए कह रहे थे, "पता नहीं यह सब एकाएक कैसे हो गया... वह तो मेरे बहुत करीबी दोस्तों में से एक है."

• टेबल टेनिस का यह एक अनूठा मैच था जो 'लव-आल' पर खत्म हुआ. सात बार राष्ट्रीय चैंपियन रह चुके **कमलेश मेहता** (27) और 1985 की महिला चैंपियन **मोनालिसा बरुआ** (25) ने जिंदगी भर के लिए साझी 'टीम' बनकर रहने का फैसला कर लिया. कमलेश बताते हैं, "तीन साल पहले हमारी दोस्ती हुई. पिछले एक साल से हम घनिष्ठ थे और पिछले हफ्ते हमने इसे स्थायी रिश्ते में तब्दील करना तय कर लिया." कमलेश बंबई में देना बैंक में काम करते हैं और मोनालिसा गुवाहाटी में ऑयल इंडिया की एक अधि-

कमलेश और मोनालिसा

कारी हैं. वे गुवाहाटी तो छोड़ने जा रही हैं पर टेनिस से नाता बना रहेगा. कमलेश कहते हैं, "मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि किसी खिलाड़ी से शादी होगी."

• फिल्मी दुनिया के [illegible] परदे से उठकर टीवी के छोटे परदे पर करतब दिखाने का फैसला करने वालों में अब दो नए नाम जुड़ने जा रहे हैं. निर्देशक-लेखक **गुलज़ार** और अभिनेता **नसीरुद्दीन शाह** 19वीं सदी के शायर 'मिर्ज़ा गालिब' पर टीवी सीरियल बनाने जा रहे हैं. स्वयं भी गीतकार और शायर की हैसियत रखने वाले गुलज़ार का कहना है, "हमारा इरादा प्रामाणिकता बनाए रखना है." गालिब की भूमिका निभाने वाले नसीरुद्दीन कहते हैं, "गालिब तो बर्नार्ड शॉ की तरह हैं. उनके काव्य में विचार के साथ-साथ व्यंग्य का भी अच्छा खासा पुट है." सीरियल का निर्देशन जगजीत सिंह तैयार कर रहे हैं.

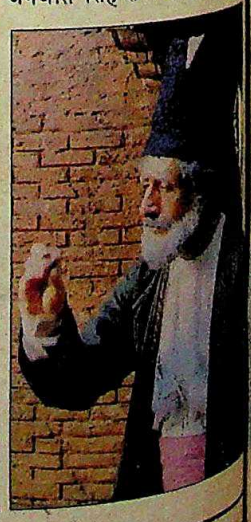

नसीर: गालिब बने

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

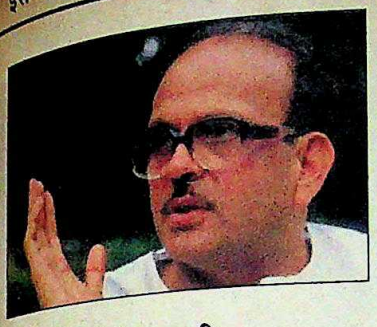

वी.पी. सिंह की जुबानी

विश्वनाथ प्रताप सिंह आखिरकार 1987 की विवादास्पद घटनाओं पर खुलकर बोले. उन्होंने रक्षा सौदों, बच्चन बंधुओं के संपर्कों, स्वीस प्रोगेती, राजीव गांधी से अपने मतभेदों और सरकार से बाहर होने से पहले की नाटकीय घटनाओं पर बेबाक बयानी की है.

आवरण कथा 46

खतरनाक खेल शुरू

खाड़कुओं के समर्थक सिख मुख्यग्रंथियों और जोधपुर में नजरबंद 40 लोगों की रिहाई के तुरंत बाद पंजाब विधानसभा भंग करने की केंद्र की कार्रवाई पंजाब के प्रति उसकी नई नीति का संकेत देती है. पर उसके एक के बाद एक उठे ये कदम खतरे से खाली नहीं हैं.

खास रपट 14

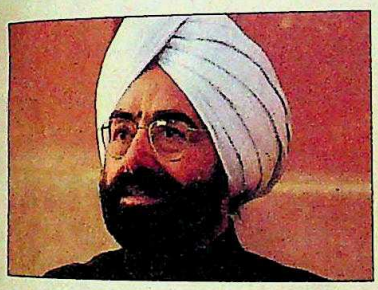

फिर विवाद का बवंडर

पूर्व राष्ट्रपति जैल सिंह ने यह कहकर धमाका कर डाला कि उन्हें दुबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 30 से 40 करोड़ रुपए देने की पेशकश की गई थी. लेकिन राजनैतिक हलकों में घबराहट पैदा कर देने के बाद ज्ञानी जी संबद्ध लोगों के नाम बताने से मुकर गए.

आजकल 20

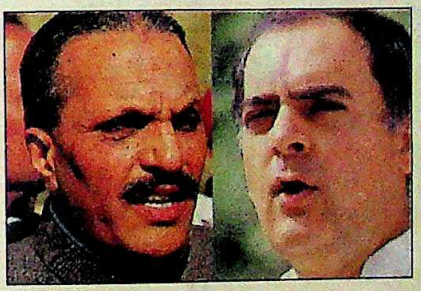

होम करते हाथ जले

अफगानिस्तान मसले में अहम भूमिका निभाने की भारत की कोशिशें साउथ ब्लॉक ने जिस फूहड़ अंदाज में कीं उससे भद ही पिटी है. राष्ट्रपति जिया को बेवक्त ही दिल्ली आने का न्यौता देकर इस्लामाबाद को भारत को परेशानी में डालने का एक मौका दिया गया.

कूटनीति 56

सबको खुश करने की कोशिश

वित्तमंत्री नारायणदत्त तिवारी ने आम आदमी को कुछ टैक्स रियायतें देकर और अपेक्षाकृत नरम बजट पेश करके करदाताओं को चौंका दिया. पर उन्होंने सरकारी वित्त का हाल बेहाल करने वाली बढ़ती मूलभूत समस्याओं को बराबर नजरअंदाज कर दिया.

कारोबार 66

विस्मृति के गर्त में खोए लोग

कलकत्ता में कभी गर्व से सिर उठाकर चलने वाला आरमेनियन समुदाय आज दीन-हीन हालत में पहुंच गया है. कभी इस महानगर के व्यावसायिक जीवन का सूत्रधार रहने वाला यह तबका पीढ़ियों के अंतराल में विस्मृति के गर्त में खोता चला जा रहा है.

विशेष लेख 38

अगले पन्नों पर

कसौटी 6
राजरंग 10
तेवर 11
हिंदोस्तां हमारा 12
बीता पखवाड़ा 13
खास रपट
पंजाब: खतरनाक खेल शुरू 14
आजकल
ज्ञानी जैल सिंह:
फिर विवाद का बवंडर 20
विपक्ष: नया उत्साह 23
दिल्ली: बच्चों पर बवाल 24
पश्चिम बंगाल: आपस में लडे और जीते ..27
इंका: बदलते दांवपेंच 28
बिहार पुलिस: तगड़ा झटका 33
तमिलनाडु: रोमांचक कथा 34
मध्य प्रदेश: संहारक अर्जुन 35
मणिपुर: तख्ता पलट गया 36
आखिरी बात 37
विशेष लेख
आरमेनियन: विस्मृति के गर्त में खोए लोग ..38
राज्य-दर्पण 45
आवरण कथा
वी.पी. सिंह:
पेचीदा व्यक्ति, उलझे विचार 46
कूटनीति
अफगान समस्या: होम करते हाथ जले 56
पास-पड़ोस
श्रीलंका: अलग सुर, अलग राग 60
व्यापार चक्र 65
कारोबार
बजट: सबको खुश करने की कोशिश 66
सिनेमा
शहंशाह: फीकी और सुस्त सवारी 72
वन्य-जीवन
पश्चिम बंगाल:
हाथियों को साधने की कठिन साधना 74
प्रतिरक्षा
'पृथ्वी': सफलता के नए सोपान 76
पड़ताल
मादक दवाएं:
सुनियोजित तस्करी का मजबूत शिकंजा 78
उड्डयन
विमान चयन: मकसद का मजाक 82
विधि-विधान
घर के चिराग से लगी आग 86
स्वास्थ्य
खेसारी दाल: पंगु हो गई सरकार 91
विकास
करघे से किस्मत चमकी 93
शिक्षा
बिहार: उच्च शिक्षा की दुकानदारी 94
टीवी
इंतजार: आत्मतुष्ट लोगों की कथा 98
रंगमंच
विभा मिश्रा: कशिश भरा नया किरदार ..99
खेलकूद
बैडमिंटन: विजय में पराजय की आहट ..100
चर्चित चेहरे 104

आवरण: भवान सिंह

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

५१ पंखे : निर्दोष मन के

बाईं ओर इन पंखों को देखते हैं आप ? ये है एक झलक हमारे ५१ किस्म के पंखों की। इतनी किस्में जिनमें पूरी हों आपकी तमाम ज़रूरतें!

मगर इन सभी में एक ख़ास चीज़ है जो बाहर से नज़र नहीं आती : निर्दोष मन।

क्योंकि आप तक पहुंचने से पहले इनमें से हर एक पंखे की १००% ऑन-लाइन जांच-परख की जाती है। इस जांच से कोई पंखा नहीं छूटता इसीलिए छूट नहीं पाती कोई दबी-छिपी खामी।

ये सब हिस्सा है पोलर की कंप्यूटरयुक्त क्वालिटी-नियंत्रण प्रणालियों का। इसीलिए तो पोलर पंखों से संतुष्ट हैं—१ करोड़ २५ लाख ग्राहक! ऐसे पंखे जिनके ३,००० डीलर हैं और भारत भर में फैले २४ सेवा केंद्र।

पोलर। ऐसी कंपनी जो वादे नहीं करती बल्कि अपनी बेहतरीन कामगिरी के सबूत पेश करती है।

पोलर

वह उत्कृष्ट कंपनी
जो बुनियाद है उत्कृष्ट पंखों की

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"धोखा खाना भला कौन पसंद करेगा"

दुनिया में सबसे बुरी अनुभूति शायद बेवकूफ बनना ही है। खास कर उस समय जब आप किसी वस्तु पर अपना विश्वास प्रकट कर चुके हों और वह बाद में बेकार साबित हो जाए। वाकई यह एक शर्मनाक स्थिति होती है। जब आप पूरे परिवार के लिए ख़ास चीज खरीदते हैं उस समय हर कोई उत्सुक होता है क्योंकि यह एक पारिवारिक खुशी का मौका होता है। और आप भी अपने आपको पुरस्कृत महसूस करते हैं जब आप देखते हैं कि आपकी मेहनत रंग लाई है।

और फिर एक हफ़्ते या एक महीने के बाद आपको पता चलता है कि आप गलती कर बैठे हैं। आप सभी के चेहरों पर मायूसी देखते हैं क्योंकि आप एक गलत वस्तु खरीद बैठे हैं और अब तो काफी देर भी हो चुकी है। आप उस वस्तु को खरीद कर फंस गए सा महसूस करते हैं और जब भी आप उस वस्तु की ओर देखते हैं आप अपने आपको बेवकूफ सा समझते हैं।

क्यों न टीवी निर्माता, टीवी खरीदने में किसी भी प्रकार के जोखिम को रहने ही न दें।

आपकी उलझन सुलझाए तमाम, जी हां, सिर्फ हॉटलाइन है नाम।

पेश है... दो साल की बेमिसाल गारण्टी।

EUROPA BY HOTLINE

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

स्वच्छता का निखार
तरो ताज़गी की बहार

भरपूर झाग और भीनी भीनी सुगंध
अंग-अंग महकाये। विशेष प्रक्रिया
त्वचा में कोमलता लाये।

निर्मल, शीतल, महक भरी ताज़गी।
ओएसिस।

खिल उठे रूप रंग
ओएसिस के संग

ओसवाल ऐग्रो मिल्स लिमिटेड का एक उत्कृष्ट उत्पादन।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इंडिया टुडे
पूर्ण समाचार पत्रिका
वर्ष 2, अंक 10 16-31 मार्च, 1988
प्रधान संपादक: अरुण पुरी
वरिष्ठ संपादक: प्रभु चावला
लिविंग मीडिया इंडिया प्रा. लि., एफ-14, कंपिटेंट हाउस, कनाट प्लेस, नई दिल्ली के लिए अरुण पुरी द्वारा संपादित और प्रकाशित तथा थॉमसन प्रेस इंडिया लि. फरीदाबाद, हरियाणा में मुद्रित.
संपादकीय कार्यालय:
लिविंग मीडिया इंडिया प्रा. लि., एफ-14/15, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001. फोन: 331 5801-4, टेलेक्स: 31-61245 INTO IN, तार: लिवमीडिया नई दिल्ली.
मुख्य सर्कुलेशन कार्यालय:
इंडिया टुडे सर्कुलेशन मैनेजर, एफ-14, कंपिटेंट हाउस, कनाट प्लेस, मिडल सर्कल, नई दिल्ली-110001. फोन: 3313076-8, टेलेक्स: 31-62634 INTO IN, तार: सर्कुलेट, नई दिल्ली.
मुख्य विज्ञापन कार्यालय:
28 ए और बी, जॉली मेकर चैंबर-2, नरीमन पाइंट, बंबई-400021. फोन: 2026152, 2029326, 2029435, टेलेक्स: 11-5373 THOM IN, तार: लिवमीडिया बंबई.
क्षेत्रीय विज्ञापन कार्यालय:
के-9, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001, फोन: 3325378, 3323575, 3321323, 3321273; टेलेक्स: 31-62124 THOM IN, तार: लिवमीडिया, नई दिल्ली; फागुन चैंबर्स, 26 कमांडर-इन-चीफ रोड, मद्रास-600105, फोन: 477188, 477770, टेलेक्स: 041-6177 INTO IN, तार: लिवमीडिया, मद्रास; 74/1, सेंट मार्क्स रोड, बंगलूर-560001. फोन: 568448, 579037, 579089, टेलेक्स: 0845-2217 INTO IN, तार: लिवमीडिया, बंगलूर; 12-सी, एवरेस्ट 46-सी, चौरंगी रोड, कलकत्ता-700016 फोन: 445398, 447726, टेलेक्स: 021-3138 INTO IN, तार: लिवइन-मीडिया, कलकत्ता.
कॉपीराइट 1984 लिविंग मीडिया इंडिया प्रा. लि. विश्व भर में सर्वाधिकार सुरक्षित. किसी भी रूप में सामग्री की नकल प्रतिबंधित. इंडिया टुडे अनिमंत्रित प्रकाशन सामग्री को लौटाने की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता.
नेपाल में 6 रुपए

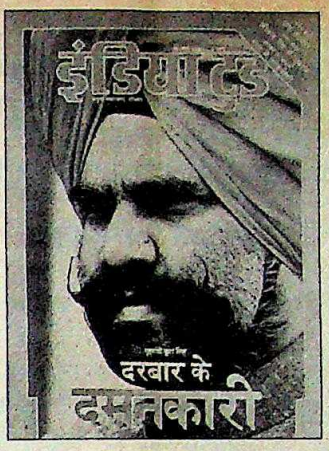

कामयाब जी-हुजूर

आवरण कथा 'दरबार के दमनकारी' (15 मार्च) पढ़कर बूटा सिंह की सफलता का रहस्य समझ में आया. निश्चित रूप से बूटा सिंह ने इतनी शक्ति चमचागीरी की बदौलत ही पाई है. राजीव दरबार में 'हां में हां' मिलाने वालों के पास ही ताकत रहती है. इसमें कोई शक नहीं कि बूटा सिंह ऐसे रोबोट के समान हैं जिसका 'रिमोट कंट्रोल' राजीव के हाथ में है.

—**दुर्गेशनंदन सिंह,** मलहीपुर (बिहार)

■ लेख में बूटा सिंह के चरित्र का सटीक और गहन विश्लेषण किया गया है. उनकी 'राजीव भक्ति' और चीमड़पन में सामंती युग की झलक मिलती है. ऐसे व्यक्ति के हाथ में इतना महत्वपूर्ण मंत्रालय सौंपना ठीक नहीं.

—**निधि,** आगरा (उ.प्र.)

■ जब नेताओं की पूरी बिरादरी ही 'हां में हां' मिलाने वालों और अवसरवादियों से भरी पड़ी है तो केवल बूटा सिंह पर ही आक्षेप क्यों? उन्हें तनखैया करार दिया गया है. यदि वे सिखों का पक्ष लेते तो शायद देशद्रोही कहलाते.

—**अरुण कुमार मिश्र,** लखनऊ (उ.प्र.)

अक्षमता का प्रतीक

'बेकार की उलटफेर' (15 मार्च) आलेख पढ़कर लगा कि यह उलटफेर ठीक वैसा ही है जैसे समय-समय पर रेल समय सारणियां बदली जाती हैं. ऊपर से यह कहना कि प्रशासन को चुस्त बनाने के लिए ऐसा किया गया है जंचता नहीं. जनता ऐसे नाटकों को कई बार देख चुकी है.

—**चेतन चौहान,** जोधपुर (राज.)

■ बार-बार मंत्रिमंडल में ये उलटफेर राजीव में आत्मविश्वास की कमी के सबूत तो हैं ही, सही व्यक्ति परखने की उनकी अक्षमता को भी दर्शाते हैं.

—**निम्मी,** अंबाला (हरियाणा)

उम्मीदों पर अड़ंगे

'परिवर्तन की उम्मीदें' (15 मार्च) पढ़कर लगा कि केंद्र अपराध और भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे बिहार का उद्धार करने के बारे में सचमुच ही गंभीरता से सोच रहा है. लेकिन राजनैतिक दबावों, भ्रष्ट नौकरशाहों के आगे नए मुख्यमंत्री कितने सफल हो पाते हैं यह देखना है.

—**अश्विनी,** कुरुक्षेत्र (हरियाणा)

■ भागवत झा आजाद की शुरुआती सख्ती और दृढ़ता देखकर तो यह आभास होता है कि वे बिहार का कायापलट करने को कटिबद्ध हैं. दरअसल बिहार जैसे राज्य को एक सख्त, पर ईमानदार और चतुर नेता की बड़ी जरूरत है. आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ही सही, केंद्र का ध्यान इस जरूरत की ओर गया तो सही.

—**उमा शर्मा,** नई दिल्ली

मार्मिक रिपोर्ट

'हादसे से उपजी हार्दिकता' (15 मार्च) दिल को गहराई तक छू गई. क्या ही अच्छा हो यदि होजई जैसे और गांव भी बनाए जाएं. कम-से-कम यहां पलकर बड़े हुए बच्चे सांप्रदायिकता के जहर से तो बचे रहेंगे.

—**अनंत प्रभाकर,** फरीदाबाद (हरियाणा)

एकतरफा विचार

कसौटी 'यों ही नहीं हैं किसान नाराज' (29 फरवरी) एकतरफा लगा. आपने यह नहीं सोचा कि किसानों की सब मांगें मान ली गईं तो दूसरे वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ेगा. गन्ने का मूल्य 35 रु. प्रति क्विंटल करने से चीनी की कीमत में जरूर वृद्धि होगी. कर्जमाफी किसी भी वर्ग के लिए क्यों न हो, इससे अकर्मण्यता को ही प्रोत्साहन मिलेगा.

—**संजय कुमार गुप्ता,** कैराना (उ.प्र.)

■ आजादी के बाद जितनी उपेक्षा कृषकों की हुई है, उतनी शायद ही किसी वर्ग की हुई होगी. हालांकि हर चुनाव में किसानों की समस्याएं हल करने का आश्वासन दिया जाता रहा है पर चुनाव के बाद सभी आश्वासन भुला दिए जाते हैं.

—**किशनसिंह पंवार,** महूगांव (म.प्र.)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

किसानों को समझें

'अद्भुत शक्ति प्रदर्शन' रिपोर्ट (29 फरवरी) में किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि और उसकी मांगों को पाठकों तक पहुंचाकर इस मुद्दे पर एक सार्थक बहस का अवसर दिया गया है. इस महत्वपूर्ण मुद्दे को राजनैतिक रूप देने के बजाय किसानों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक समझकर उनका समाधान ढूंढ़ना ज्यादा उचित होगा.

—नरेंद्र सिंह, मारवाड़ (राज.)

यह बहादुरी नहीं

'दहेज की बलि' (29 फरवरी) पढ़ा. तीन बहनों ने दहेज के विरोध में आत्महत्या करके जहां सामाजिक व्यवस्था पर करारा तमाचा मारा है, वहीं कायरता का भी परिचय दिया है. पढ़ी-लिखी पोस्टग्रेजुएट लड़की को यह सब शोभा नहीं देता. उन्हें तो अपने योग्य ऐसे युवकों को खोजना चाहिए था, जो दहेज विरोधी होते.

—राजेश मदौरिया, ग्वालियर (म.प्र.)

■ कोई नारा या कानून उस समाज में कैसे प्रभावकारी हो सकता है, जिसमें एक बेटे की चाह में बेटियों की कतार लगा दी जाती है. लड़के के लिए 'लड़का' होना ही काफी है, शिक्षा, रूप-गुण सब गौण. और लड़की का यह सोचना भी 'अनहोनी' कि निर्लज्ज 'भिखारियों' के हाथ पड़ने से बेहतर है कि अपने पैर पर खड़ी हों.

—नीना अरोड़ा, चंडीगढ़

■ यह घटना भारतीय समाज के लिए शर्मनाक है. 40 और 80 हजार रुपयों से भी ज्यादा दहेज चाहने वाले क्या किसी भी तरह दंडित या प्रताड़ित नहीं किए जा सकते. कहां हैं हमारे महिला संगठन व उनके स्वनामधन्य नेता?

—मनमोहन द्विवेदी, उज्जैन (म.प्र.)

मधुर संगीत का कमाल

'पुरानी फिल्में: दूसरी पारी में भी जमीं' (29 फरवरी) पढ़ा. इन फिल्मों की लोकप्रियता का प्रमुख कारण मधुर संगीत और भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत कहानियां हैं.

—रमेश कुमार साहू, पानीतोला (असम)

■ छठे और सातवें दशक की फिल्मों का संगीत ही कुछ और था. आज की डिस्को लहर से दर्शक ऊब चुका है. वही हिंसा, मारधाड़ और दोहराये हुए विषय पर बन रही फिल्मों के मुकाबले पुरानी संगीतमय और प्रेम कहानियों पर बनी फिल्में दर्शकों को ज्यादा पसंद आ रही हैं.

—प्रतापसिंह हजारी, पुणे (महाराष्ट्र)

चिंताजनक स्थिति

'चले अढ़ाई कोस' (29 फरवरी) पढ़ा. बेहद सटीक रिपोर्ट थी. उसमें जो आंकड़ों का लेखा-जोखा था, उससे हमारी स्वास्थ्य सेवाओं की कमी उजागर होती है. बच्चे ही भविष्य हैं. हमारे स्वास्थ्य संगठन और सामाजिक संस्थाओं को अपनी तमाम समस्याओं के बावजूद इस ओर ध्यान देना चाहिए.

—संजय जैन, मूर्तिजापुर (महाराष्ट्र)

आदमी की कीमत पर

छायालेख 'नरभक्षी बाघों का कहर' (29 फरवरी) पढ़ा. समझ में नहीं आता कि मनुष्यों की जान की कीमत पर बाघों (नरभक्षी) को क्यों जिंदा रखा जा रहा है? अगर पश्चिम बंगाल सरकार नरभक्षी बाघों का सफाया नहीं कर सकती तो वह सुंदरवन के लोगों को रोजगार मुहैया कर उन्हें कहीं और बसाने की व्यवस्था क्यों नहीं करती?

—डी.एन. सिंह, बेगूसराय (बिहार)

प्रदूषित पत्रकारिता

'आज' का 'जागरण' युद्ध (29 फरवरी) पढ़कर लगा कि पत्रकारिता प्रदूषित हो गई है. अपने संपादकीय लेखों में सत्य, अहिंसा, ईमानदारी का उपदेश देने वाले आपस में जिस प्रकार लगभग एक साल से सिर-फुटौव्वल कर रहे हैं, उससे निश्चय ही उनके खोखले और निरर्थक दावों का पर्दाफाश ही हो रहा है.

—राजीव कुमार सचान, इलाहाबाद (उ.प्र.)

स्पष्टीकरण

अपनी रिपोर्ट 'आज' का 'जागरण' युद्ध (29 फरवरी) के सिलसिले में हम कहना चाहते हैं कि विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय ने 1987-88 में दैनिक 'जागरण' की प्रसार संख्या 3.84 लाख मानी है. यह आंकड़ा उत्तर प्रदेश में उसके सात संस्करणों का है. निदेशालय 'आज' के छह संस्करणों की प्रसार संख्या 3.19 लाख मानता है. इसके अलावा ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ने जनवरी से जून 1987 तक 'आज' के इलाहाबाद संस्करण की प्रसार संख्या 29,291 मानी है जिससे 'आज' की कुल प्रसार संख्या 3.49 लाख पर पहुंच जाती है. यह आंकड़ा उत्तर प्रदेश और बिहार में उसके सभी संस्करणों का है.

इस रिपोर्ट में भूल से कानपुर 'जागरण' की प्रसार संख्या 1.47 लाख की जगह 1.17 लाख छप गई थी.

—संपादक

समान कानून जरूरी

'निगलते बने न उगलते' (29 फरवरी) पढ़ा. यह एक कड़वा सच है कि मुस्लिम समाज में औरतों की हालत बहुत बदतर है और कम-से-कम एक ऐसा कानून तो होना ही चाहिए जिससे जबानी तलाक देने की प्रथा खत्म हो. मुस्लिम समाज को जरूरत है रेखा दीक्षित जैसी साहसी जजों की, न कि नाकाम प्रधानमंत्री की. यह समस्या जड़ से तो तब ही खत्म होगी, जब देश में एक समान कानून होगा.

—साहिबे आलम, हापुड़ (उ.प्र.)

देश का दिवाला

'राष्ट्रीय कर्ज़: फंदे में फंसी अर्थव्यवस्था' (29 फरवरी) पढ़कर दिल दहल गया. सरकार की गलत आर्थिक नीतियों ने ही देश को कर्ज के फंदे में फंसा दिया है. यह बढ़ता कर्ज आने वाली पीढ़ियों पर बोझ बना रहेगा और टैक्स द्वारा जनता से ही वसूला जाएगा.

—सुनील कुमार सिंह, पटना (बिहार)

■ लेख में आपने भारत को चौथा सबसे बड़ा कर्ज लेने वाला देश बताया है, जबकि आपके आंकड़े ही बताते हैं कि भारत का स्थान तीसरा है. जैसे ब्राजील 7389.4 करोड़ डॉलर, मैक्सिको 7251 करोड़ डॉलर, भारत 2974.4 करोड़ डॉलर और कोरिया गणराज्य 2912.6 करोड़ डॉलर के कर्ज में डूबे हैं.

—विनोद नाथ, चंदौसी (उ.प्र.)

■ भूल के लिए खेद है.

—संपादक

विकृत इतिहास

'विवादों की चांदमारी' (29 फरवरी) के माध्यम से आपने एक सशक्त सीरियल का बेबाक विश्लेषण किया है. भीष्म साहनी और गोविंद निहलाणी जैसे सिद्धहस्त लेखक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

समय के अथाह सागर में, ये घड़ियाँ हैं उसके खेलने की.
बेफिक्री के ज़माने की. पर ज़िंदगी में तो ज़रूरत पड़ेगी समय
की पाबंदी उठाने की.

४५० लाख लोगों ने समय की पाबंदी की निराली राह अपनायी है.
ये घड़ी है उसके खेलने की. सीखने और समझने की...
मुट्ठी भर रेत और समय में फर्क जानने की.

hmt
घड़ियां

राष्ट्र के समय प्रहरी

Sista's-1489/88 Hin

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Coll

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

और निर्माता, निर्देशक से यही उम्मीद हमें भी थी, मगर अफसोस है कि निहलाणी ने इतिहास को विकृत करके दर्शकों के सामने रखा है. —**शिवपूजन तिवारी,** उन्नाव (उ.प्र.)

■ 'तमस' एक आईना है जिसमें सांप्रदायिक ताकतों का घिनौना चेहरा नजर आता है. यह ऐतिहासिक घटनाक्रम का ही एक अध्याय है पर लेखक व निर्माता को किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं होना चाहिए था.

—**श्याममनोहर व्यास,** उदयपुर (राज.)

नौकरशाहों से घिरे नेता

आवरण कथा 'राजीव गांधी: नया रूप, बदलते मिजाज' (29 फरवरी) पढ़कर लगा कि राजीव देश की समस्या सुलझाने के बजाय अपने आप में ही उलझ गए हैं. कुल मिलाकर वे अपने नौकरशाहों और चमचों से घिर गए हैं. जहां पहले वे घूम-घूमकर जनता के सुख-दुख का समाचार लेते थे, अब अपने नौकरशाहों द्वारा दिए गए झूठे आंकड़ों के बूते पर देश को 21वीं सदी में ले जाने का ख्वाब देख रहे हैं.

—**जितेंद्र कुमार उपाध्याय,** बंगलूर (कर्नाटक)

■ आवरण कथा के पैने विश्लेषण और सारगर्भित तथ्य ने मन मोह लिया. पर आश्चर्य है कि 1984 के राजीव 1988 के राजीव में कैसे और क्यों बदल गए, इस तथ्य का विश्लेषण नहीं किया गया है. एक व्यक्ति यदि समाज को बदल सकता है तो राजीव दोषी हैं, अन्यथा समाज. तो फिर राजीव पर दोष थोपना क्या उचित है?

—**राजकुमार,** बीएचयू, वाराणसी (उ.प्र.)

■ समय के साथ-साथ किसमें परिवर्तन नहीं आता. फिर युवा और अनुभवहीन नेता अनुभवों का खट्टा-कसैला स्वाद लेकर ही तो अनुभवी बन सकेगा. हां, उन्हें सही मार्ग-दर्शन की सख्त जरूरत है.

—**सुरेश वर्मा,** अंबाला (हरियाणा)

आश्चर्यजनक नतीजे

जनमत संग्रह के परिणाम बहुत आश्चर्य-जनक हैं. हम तो यही सोचते थे कि राजीव गांधी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण उनका इस बार चुनाव जीतना बहुत मुश्किल होगा. इसका सबसे बड़ा कारण विपक्षी पार्टियों में एकता का अभाव ही हो सकता है. चुनाव की घोषणा होते ही विपक्ष एक हो जाए तब तस्वीर बदल सकती है.

—**अशोक कुमार,** मेरठ कैंट (उ.प्र.)

■ विशेष जनमत संग्रह की शैली व डिसप्ले अच्छा लगा लेकिन उसके कुछ तथ्य पक्ष-पातपूर्ण लगे. सर्वेक्षण में वी.पी. सिंह के मुकाबले राजीव गांधी को अधिक ईमानदार बताया गया जबकि पिछले एक वर्ष के घटनाक्रम में राजीव गांधी ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है जिससे उनकी ईमान-दारी साबित होती हो.

—**कृष्णकांत कुलश्रेष्ठ,** आगरा (उ.प्र.)

■ गरीब और अशिक्षित जनता का ही इंका की तरफ ज्यादा झुकाव है. और जनता जब तक गरीब व अशिक्षित रहेगी तब तक तो कांग्रेस का ही वर्चस्व रहेगा क्योंकि भारत की 65 फीसदी जनता गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रही है.

—**मुनिया चौहान,** पाली (राज.)

दकियानूसी रवैया

'हरिजन होना गुनाह' (29 फरवरी) पढ़ा. कितने शर्म की बात है कि हम एक ओर देश को 21वीं सदी में ले जाने की बात करते हैं, दूसरी ओर सदियों पुरानी जमींदारी प्रथा और छुआछूत जैसी दकियानूसी हरकत करने से बाज नहीं आते.

—**शैलेंद्र सिंह 'बडे',** खरगौन (म.प्र.)

यदि आपका जन्म १९६३ से पहले हुआ है तो इस विज्ञापन को ध्यान से पढ़िए

२५ साल से अधिक उम्र वाले १० में से ९ लोगों के बाल झड़ रहे हैं.... लेकिन उन्हें इसका पता नहीं!

क्या आप उन ९ लोगों में से एक हैं? तब तो आज ही यह परीक्षण कीजिए

अपने बालों को ज़ोरों से कंघी कीजिए. अगर कंघी पर बाल उतर आएं तो समझ लीजिए आपके बाल झड़ रहे हैं.

इसका हल है — प्योर सिल्विक्रिन

बालों के झड़ने का कारण है — ज़रूरी अमिनो एसिड्स की कमी — जो आपके बालों की कुदरती ख़ुराक है. केवल प्योर सिल्विक्रिन में ही वैज्ञानिक अनुसंधान से बना वह फार्मूला है जो इस कमी को पूरा करता है.

इसके कारण हैं:

१. प्योर सिल्विक्रिन १७ अमिनो एसिड्स का अनोखा मिश्रण है — आपके बालों की कुदरती ख़ुराक.

२. नोबेल पुरस्कार विजेता अनुसंधान तकनीक यह प्रमाणित करती है कि प्योर सिल्विक्रिन बालों की जड़ों तक बहुत जल्दी पहुंचता है, बालों में कुदरती ख़ुराक की कमी पूरी करता है और बालों को फिर से स्वस्थ बनाता है.

उत्तम परिणाम के लिए प्योर सिल्विक्रिन को सर की त्वचा पर तब तक प्रतिदिन दो बार मलिए जब तक आपके बालों का स्वास्थ्य सामान्य नहीं हो जाता.

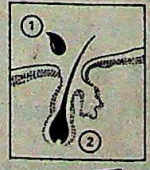

प्योर सिल्विक्रिन असरदार है — नोबेल पुरस्कार विजेता अनुसंधान तकनीक का प्रमाण.

प्योर सिल्विक्रिन

Gurukul Kangri Collection, Haridwar

इंडिया टुडे
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कसौटी

अंधी गली में लोकतंत्र

अंग्रेजों ने भारत को आजाद करके उसे सत्ता आधी रात में क्या सौंपी कि लगता है आजकल कांग्रेस ने उसे एक नई परंपरा ही बना डाली है. कांग्रेस शासित राज्यों में पिछले दिनों ऐसा ही कुछ हुआ. मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री को आधी रात के बाद लगभग तीन बजे शपथ दिलाई गई. और तो और, नए नेता के चुनाव के लिए इंका विधायक दल की उपयुक्त बैठक भी नहीं की गई क्योंकि कोरम की संख्या जितने सदस्य ही नहीं बुलाए जा सकते थे. बिहार में भी भागवत झा आजाद को इसी तरह पौ फटने में कुछ पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई. और मणिपुर में तो पदासीन मुख्यमंत्री रिसांग कीशिंग ने इस्तीफा देने से इनकार ही कर दिया. केंद्रीय गृहमंत्री बूटा सिंह ने एक तरह से उनकी बाजू पकड़कर उनसे अपने उत्तराधिकारी के नाम के प्रस्तावना पत्र पर दस्तखत करवाया. केवल राजस्थान में ही इंका विधायकों को अपनी बात कहने की इजाजत दी गई लेकिन उनका बहुमत जबकि हीरालाल देवपुरा के पक्ष में था, मुख्यमंत्री बने आलाकमान की पसंद के शिवचरण माथुर ही.

रेखाचित्र: अजीत नाइनन

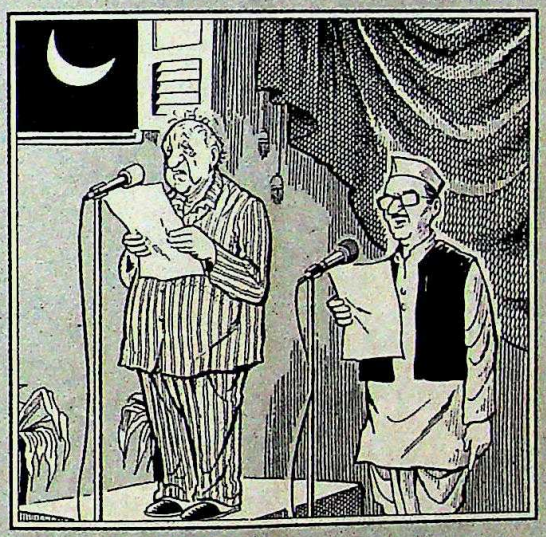

मगर इस तमाम नाटकबाजी से हासिल क्या हुआ है? मणिपुर के नए मुख्यमंत्री आर.के. जयचंद्र सिंह अपने राज्य में आज तक कोई चुनाव नहीं जीत पाए हैं. मध्य प्रदेश के 'नए' मुख्यमंत्री वास्तव में दक्षिण दिल्ली से निर्वाचित संसद सदस्य हैं. और बिहार के विधायक विदेश्वरी दुबे केंद्रीय कानूनमंत्री बना दिए गए हैं तो मध्य प्रदेश के विधायक मोतीलाल वोरा केंद्रीय स्वास्थ्यमंत्री. यह सब संसदीय लोकतंत्र का मजाक नहीं तो और क्या है. संसद और विधान-सभाओं की सदस्यता को बेमानी कर दिया गया है. नतीजा यह कि ठीकठाक चल रहा राज्य प्रशासन अस्थिर हो जाता है और जिन विधायकों की अनदेखी की जाती है उनकी असंतुष्ट चुप्पी के बावजूद गुटबंदी को बढ़ावा मिलता है.

समझ में नहीं आता कि इतनी अफरातफरी किस बात की है कि मुख्यमंत्रियों को आधी रात शपथ दिलाने की नौबत आ गई थी. क्या इतने महत्वपूर्ण काम दिन की रोशनी में नहीं हो सकते? विधायक दल की उपयुक्त बैठक क्यों नहीं बुलाई जा सकती ताकि लोकतंत्र का कम-से-कम मुलम्मा तो कायम रहे. आलाकमान क्या ऐसा करके किसी भी विरोध की संभावना को मिटा देना चाहता है या वह पार्टी विधायकों की औपचारिक सहमति की भी जरूरत नहीं समझता. यह कांग्रेस पार्टी की दुरावस्था का ही परिचायक है कि एक व्यक्ति के मनमाने शासन का विरोध करने की कोई हिम्मत तक नहीं करता.

पार्टी के अंदरूनी लोकतंत्र को सबसे पहले इंदिरा गांधी ने नुकसान पहुंचाया था, पार्टी संगठन के चुनाव न करवाकर और बाद में मनमाने तरीके से मुख्यमंत्रियों को नियुक्त करके. लेकिन वे एक तरह का छद्म जरूर बनाए रखती थीं—सलाह-मशविरा, वरिष्ठ नेताओं को सूचित करना, विधायकों की राय जानने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों को भेजना आदि सब कुछ होता था उन दिनों. लेकिन हर कोई जानता था कि होगा वही जो वे तय करेंगी. कुल मिलाकर वह भी 'नियंत्रित' लोकतंत्र था, वास्तविक लोकतंत्र नहीं. लेकिन सार्वजनिक और संवैधानिक मूल्यों के सम्मान का कम-से-कम दिखावा तो होता था.

आज वह भी नहीं होता. अर्जुन सिंह ने इस तथ्य का खंडन करने की भी जरूरत नहीं समझी कि विधायक दल की जिस बैठक में उन्हें नेता चुना गया उसमें कोरम पूरा नहीं था—248 इंका विधायकों में से सिर्फ 35 ही उपस्थित थे. और कांग्रेस के संविधान का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन किया गया. इस संविधान के अनुसार विधायक दल की बैठक की सूचना एक हफ्ते पहले दी जानी चाहिए थी. लेकिन जो सूचना भेजी गई वह जिला प्रशासन को, सरकारी संचार तंत्र के जरिये. प्रशासन से कहा गया कि वह विधायकों को इकट्ठा करके तुरंत राजधानी की ओर रवाना करे. बिहार के मामले में तो यहां तक हुआ कि जो विधायक दिल्ली में थे उन्हें बीएसएफ के विमान से पटना पहुंचाया गया. कई छूट गए क्योंकि विमान में जगह नहीं थी. और नए मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने के लिए राज्यपाल उधर देर रात तक घंटों इंतजार करते रहे. मणिपुर में जयचंद्र सिंह को बूटा सिंह खुद राजधानी ले गए और बेचारे कीशिंग को एक तरह से जबरदस्ती गद्दी छोड़नी पड़ी.

कौन करता है इस तरह के अजीबोगरीब फैसले? और इन फैसलों तक पहुंचने की प्रक्रिया आखिर क्या है? सामान्य शिष्टाचार का पालन, ऊंचे पद पर बैठे व्यक्तियों को सम्मान देना आखिर क्यों संभव नहीं है? जाहिर है पार्टी के भीतर सलाह-मशविरे की प्रथा को तिलांजलि दे दी गई है. विधायक दल की बैठक की बात छोड़ भी दें तो न तो कांग्रेस कार्यकारी समिति और न ही कांग्रेस संसदीय बोर्ड से कोई मशविरा किया गया. लगता है जैसे पार्टी रबड़ की एक मुहर भर रह गई है. यहां हर आदमी ऊपर के हुक्म के आगे घुटने टेकता चला जा रहा है, शर्मनाक आचरणों के खिलाफ कोई चूं तक नहीं कर पाता.

राज्यपाल जैसे सम्माननीय और महत्वपूर्ण पद का दुरुपयोग (जैसा कि आंध्र प्रदेश में हुआ), सदन में इंकाई सांसदों और मंत्रियों के अशोभनीय व्यवहारों पर राज्यसभा के अध्यक्ष की क्षुब्ध होकर इस्तीफा तक दे देने की अभूतपूर्व पेशकश, मेघालय में शर्मनाक तरीके से इंका सरकार की स्थापना— इन तमाम बातों को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो यही लगेगा कि प्रधानमंत्री और उनकी मेरुदंडहीन पार्टी भारतीय लोकतंत्र को जिस राह पर ले जा रही है उस पर सवाल उठाया ही जाना चाहिए.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तू नहीं और सही

● विदेश मंत्रालय कई बार तो कुछ अजीब-सी परिस्थितियों में फंस जाता है पर कुछ हाजिरजवाब अफसर उसे उबार लेते हैं. पिछले पखवाड़े उत्तरी कोरिया के प्रधानमंत्री किम इल सुंग की दिल्ली यात्रा के दौरान भी ऐसी ही कुछ नौबत आ गई. सामान्य प्रोटोकोल वाली मेल-मुलाकातों के बाद विदेश

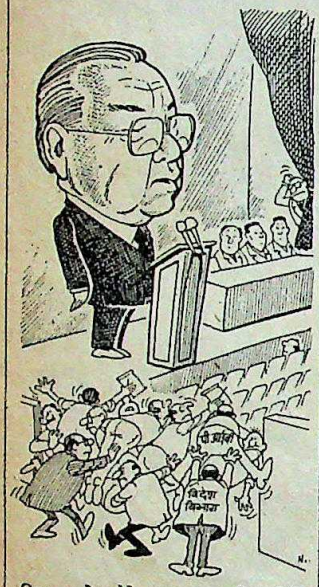

विभाग ने दौरे पर आए वीआईपी के लिए शास्त्री भवन में एक प्रेस कान्फ्रेंस आयोजित की. लेकिन उस दिन भारतीय पत्रकारों के पास प्योंग्योंग की राजनीति पर चर्चा करने से भी महत्वपूर्ण कई काम थे. लिहाजा प्रेस कान्फ्रेंस जब शुरू हुई तो पूरा हॉल लगभग खाली पड़ा था.

इससे विदेश विभाग के परेशान अधिकारी कमरे को भरने के लिए बेतरह लोगों की खोज में जुट गए. आखिर वे प्रेस सूचना केंद्र के कुछ अधिकारियों को जुटाकर बतौर संवाददाता पेश करने में कामयाब हुए. इस तरह सिरे चढ़ी विदेशी मेहमान की यह प्रेस कान्फ्रेंस.

समझदारी का काम

● अमेरिका और रूस के पदचिन्हों पर चलते हुए कुछ साल पहले भारत और पाकिस्तान ने भी नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच एक इमरजेंसी हॉटलाइन की स्थापना की ताकि संकट के समय तुरतफुरत संबंध कायम किया जा सके. भारत के विदेश सचिव के फोन का चोंगा उठाते ही इस्लामाबाद में उनके समकक्ष का फोन घनघना उठता. पिछले दिनों जब भारत के विदेश सचिव ने फोन का चोंगा उठाया तो दूसरी तरफ फोन की घंटी बजी ही नहीं क्योंकि पाकिस्तानियों ने अपने तरफ की लाइन काट दी थी. एक पाकिस्तानी कूटनयिक ने बताया, "यह व्यवस्था भयानक रूप से खर्चीली थी और पिछले दो सालों में इसका उपयोग सिर्फ एक बार ही हुआ." इसलिए एसटीडी से ही भली-भांति काम चलेगा."

कंप्यूटर की कसरत

● राज्यसभा की उम्मीदवारी के लिए इंका में दौड़धूप शुरू हो गई है. पार्टी के 50 से अधिक लोगों का कार्यकाल इसी महीने पूरा हो रहा है. उम्मीद है कि सिर्फ एक कार्यकाल पूरा करने वालों को नामजद किया जाएगा जबकि दो कार्यकाल पूरा करने वालों की 'योग्यता के आधार' पर जांच की जाएगी. तीन बार राज्यसभा सदस्य रह चुके पार्टीजनों को मौका नहीं मिलेगा.

राजीव ने ऐसे सभी सांसदों और 500 आवेदकों (जिनमें छह

पत्रकार भी हैं) का बायोडेटा व्यक्तिगत कंप्यूटर में डाल दिया. पिछले पखवाड़े सूची को अंतिम रूप देने के लिए वे चार घंटे तक कंप्यूटर से जूझते रहे. आश्चर्यजनक रूप से उसमें चार ऐसी महिलाओं के नाम, सामने आए जो हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय में देखी गई थी. उन्हें लोकसभा अध्यक्ष की गैलरी में भी अक्सर ऐसे समय देखा गया है जब राजीव संसद में उपस्थित होते हैं.

बस प्राइम मिनिस्टर!

● जी हां, यह बिलकुल सच है. भारत के प्रधानमंत्री भी बीबीसी द्वारा बनाए गए मजाकिया टीवी

सभी कार्टून: अजीत नाइनन

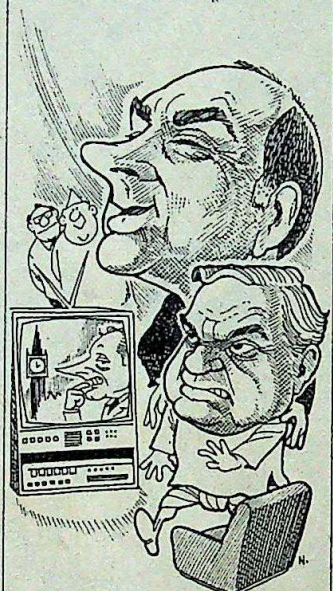

सीरियल 'यस, प्राइम मिनिस्टर' को बिला नागा देखते रहे हैं.

इसमें दिखाया गया है कि मजबूती से पैर जमाए अफसरशाही किस तरह तिकड़में भिड़ाती है और यदि उसे अपनी पकड़ पर आंच आती दिखे तो कई बार भोलेभाले प्रधानमंत्री की इच्छाओं पर भी पानी फेर देती है. दूरदर्शन पर दिखाए गए इस 'हिट' सीरियल से राजीव गांधी बहुत प्रभावित हुए. उन्होंने अपने घर के लोगों से बोल रखा था कि काम में व्यस्त होने या किसी और वजह से यदि वे इसे न देख पाएं तो सीरियल को टेप कर लिया जाए ताकि उसे बाद में देखा जा सके.

बताया जाता है कि इस सीरियल की वह कड़ी राजीव को विशेष रूप से भा गई जिसमें सुरक्षा व्यवस्था की एक गड़बड़ी के मामले में आम तौर पर प्रधानमंत्री के खिलाफ षड्यंत्र करते रहने वाले गृह सचिव और कैबिनेट सचिव को आपस में भिड़ते दिखाया गया है. राजीव इसके इस कदर दीवाने बन गए कि संसदीय सलाहकार समिति की हाल ही की एक बैठक में उन्होंने भाजपा के नेता अटलबिहारी वाजपेयी से भी इसे देखने का आग्रह किया.

ये भी हैं, वो भी हैं

● पश्चिम बंगाल से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद सैफुद्दीन चौधरी अपने तेजतर्रार तेवर के लिए प्रसिद्ध हैं. लेकिन तेजतर्रारी के कारण उनमें लापरवाही वाली बात नहीं आई है वे सधी जबान वाले ऐसे सतर्क व्यक्ति हैं जो सदन में किसी मसले पर वाद-विवाद के दौरान शायद ही किसी को आगे निकलने देते हैं. लेकिन अपवाद तो हर जगह होता ही है. पिछले पखवाड़े सांसद महोदय फिर हमले की मुद्रा में थे. इस बार हमले का मुद्दा यह था कि भारत सरकार ने विदेशी, खासकर अमेरिकी और पश्चिमी यूरोप के जहाजों को अपने बंदरगाहों पर लंगर डालने की मंजूरी क्यों कर दे दी. सरकार के इस फैसले से वे काफी नाराज थे.

विदेश राज्यमंत्री नटवर सिंह ने जवाब में कहा कि कई सालों की तरह इस साल भी अमेरिकी जहाजों की तुलना में रूसी जहाजों ने ही ज्यादातर भारतीय बंदरगाहों पर

लंगर डाले. इसके अलावा नटवर सिंह ने यह टिप्पणी भी की, "लेकिन इस मामले में मुझे शक है कि माकपा ने गोर्बाचेव की ग्लासनोस्त (खुलेपन की नीति) का अध्ययन भी किया है या नहीं."

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

• मैं उनके (राष्ट्रपति चुनाव दोबारा लड़ने के लिए पैसे खर्च करने की पेशकश करने वालों के) नाम क्यों बताऊं. मुझे अपने दोस्तों को तो बचाना है.

■ **जैल सिंह,** *नवभारत टाइम्स*

• राजीव गांधी मेरे सामने बच्चे हैं. मैं तो उन्हें अच्छी सलाह दूंगा. अगर वह मेरी बात नहीं मानते तो जाएं चूल्हे में गिरें.

■ **कमलापति त्रिपाठी,** *चौथी दुनिया*

• अब यह फैसला सरकार को करना है कि वह हमें देश के भीतर आजादी देगी या देश के बाहर.

■ **जत्थेदार जसबीर सिंह** (रिहा होने के बाद), *जनसत्ता*

• राजीव गांधी को लगता है कि सिखों का दमन करके शासन चलाने से ही उनकी कुर्सी बची रहेगी.

■ **प्रकाश सिंह बादल,** *संडे मेल*

• विपक्ष की एकता के लिए कोई तंबू-कनात तो हमें गाड़ने नहीं हैं...जिन लोगों को लगता है कि विपक्ष बिखरा हुआ है, वे सरासर गलतफहमी में हैं.

■ **हेमवतीनंदन बहुगुणा,** *नई दुनिया*

• बुढ़ापे में भारत भ्रमण करने वाले मुख्यमंत्री (देवीलाल) किसानों के हित में क्या सोचेंगे?

■ **सत्यप्रकाश मालवीय,** *दैनिक ट्रिब्यून*

• बंसीलाल कांग्रेस के वह हवलदार हैं जो पार्टी की पद रूपी वर्दी पहने हों तो गुर्राते हैं और जब उनसे पद छिन जाता है तो उनकी बोलती बंद हो जाती है.

■ **ओमप्रकाश चौटाला,** *पंजाब केसरी*

• जब मैं स्ट्रोक लगाकर खेलता हूं तो भी मेरी आलोचना होती है और स्ट्रोक नहीं लगाता तब भी मेरी आलोचना होती है.

■ **कृष्णमाचारी श्रीकांत,** *स्पोर्ट्सवीक ऐंड लाइफस्टाइल*

• अब मैं 'राम तेरी गंगा मैली' जैसी और फिल्म में काम नहीं करूंगी.

■ **मंदाकिनी,** *फिल्मफेयर*

• काला धन? न.न. मैं तो इसे छूता तक नहीं—यह बयान उतना ही सही है जितना यह कि राजीव गांधी ने डोल्फिन नहीं व्हेल को बचाया था.

■ **शत्रुघ्न सिन्हा,** *स्टारडस्ट*

• हिंदी सिनेमा लावारिस है. वह बंबई के बाजार में पैदा होता है. उसकी परवरिश करना आप लोगों की ही जिम्मेदारी है.

■ **बासु भट्टाचार्य,** *नई दुनिया*

भरिए

यह कूपन और अपनी चहेती आवाज़ सुनिए: बच्चे की खिलखिलाहट

हंसी-खुशी और मौज-मस्ती बच्चों के लिए उतनी ही ज़रुरी हैं जितने ज़रुरी हैं खाना-पीना और हवा. और डिस्नी टुडे लेकर आया है यही मस्ती... यही मज़े.
बस तो फिर यह कूपन भर दीजिए और हर एक को खुश कर दीजिए.

आकर्षक छूट का लाभ उठाईये.

कूपन निम्नलिखित पते पर भेजें:
लिविंग मीडिया इंडिया (प्रा.) लि.
सबस्क्रिपशन डिपार्टमेंट
थॉमसन प्रेस बिल्डिंग
पो.बॉ. न० 69, दिल्ली-मथुरा रोड
फ़रीदाबाद - 121 007 (फ़रीदाबाद)

मुझे अपने बच्चे के लिए सबस्क्रिपशन चाहिए. यह रहा मेरा सालाना सबस्क्रिपशन ☐ हिंदी रु. 78/- ☐ अंग्रेजी रु. 96/- प्रति के लिए. मैं भुगतान चैक/मनी आर्डर/डिमांड ड्राफ्ट नं. _____ द्वारा कर रहा हूं.

कृपया प्रति निम्नलिखित नाम व पते पर भेजें:
नाम _____
उम्र _____ लिंग _____
डाक-पता _____
_____
_____
विद्यालय : _____
माता-पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर _____
कृपया भुगतान लिविंग मीडिया इंडिया (प्रा०) लि० के नाम पर बनाएं.

© 1987 THE WALT DISNEY CO., USA.

Disney's डिस्नी टुडे
अब उपलब्ध हर पखवाड़े हिन्दी और अंग्रेज़ी में

MILESTONES/DT/114 Hin a

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वायरलेस की बदौलत

■ बढ़ते अपराधों और आतंकवाद के दौर को देखते हुए दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों के साजसामान में जिन उपकरणों में भारी बढ़ोतरी की गई है उनमें वायरलेस भी हैं. कोई सूचना अब कुछ क्षणों

सभी कार्टून: अनिल शर्मा

में ही वरिष्ठ अधिकारियों और बाकी पुलिसवालों तक पहुंचाई जा सकती है. इरादा यही है कि समय रहते ही आतंकवादियों के भागने के रास्ते बंद किए जा सकें. मगर यह सुविधा भी जी का जंजाल सिद्ध होने लगी है.

वरिष्ठ अधिकारियों के पास कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारी इन वायरलेस सेटों का इस्तेमाल अपने परिवार तक निजी संदेश भिजवाने या दूसरे व्यक्तिगत कामों के लिए करने लगे हैं. कर्मचारियों के लंबे ड्यूटी घंटों को देखते हुए अक्सर इन शिकायतों को अनदेखा कर दिया जाता है. लेकिन पिछले दिनों वायरलेस के माध्यम से दिल्ली के पुलिसवालों को जो कुछ सुनने को मिला वह अपनी तरह का अनूठा अनुभव था. आतंकवादियों के बारे में जानकारी पाने के लिए वायरलेस सेटों पर कान सटाकर बैठे अधिकारी उस समय चौंक गए जब कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का नाम ले लेकर गालियों की बौछारें प्रसारित होने लगीं. बाद में जांच करने पर पता चला कि यह काम संचार विभाग में तैनात एक हेड कांस्टेबल का था जो नशे में धुत्त होकर वायरलेस के सामने अपनी भड़ास निकाल रहा था. फिलहाल इस कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है.

लॉटरी का चक्कर

■ लॉटरी पाने के लिए लोग देवी-देवताओं की मन्नत मनाने से लेकर टोने-टोटके तक क्या-क्या नहीं करते? लेकिन उस बेचारे के बारे में क्या कहा जाए जिसकी लॉटरी तो निकल आई हो मगर लॉटरी अधिकारियों तक पहुंचने से पहले ही उसके टिकट का हुलिया धोबी के हाथों बिगड़ जाए?

पिछले महीने बंबई के बेवानदास लोहाणा ने जब लॉटरी का परिणाम देखा तो उसकी खुशी की सीमा न रही. महाराष्ट्र राज्य सरकार की लॉटरी में उसका 25 लाख रुपए का इनाम निकला था. मगर किस्मत की मार देखिए कि बुखार ने उसे कुछ दिन के लिए ऐसा जकड़ लिया कि बेचारा लॉटरी कार्यालय भी नहीं जा सका. जब वह भला-चंगा होकर लॉटरी के दफ्तर के लिए निकला तो पता चला कि टिकट ही गायब है. टिकट ढूंढ़ने के लिए धूम मची तो आखिर में वह उस कमीज की जेब में से निकला जो धोबी के यहां से धुलकर आई थी.

हालांकि टिकट का नंबर पढ़ा जा सकता था पर लॉटरी अधिकारियों ने इस आधार पर इनाम देने से मना कर दिया कि टिकट की हालत खस्ता है.

अब बेवानदास ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई. पिछले पखवाड़े मामला अदालत के सामने पेश

हुआ और अदालत ने राय दी कि बेवानदास की फरियाद को गंभीरता से सुना जाना चाहिए था. अदालत की बात मानते हुए अब लॉटरी विभाग ने आश्वासन दिया है कि ऐसा ही किया जाएगा.

सायरन का हौआ

■ पिछले पखवाड़े गिरिडीह के नागरिकों और पुलिस को जो नाच एक बैंक के सायरन ने नचवाया उसे वे आसानी से नहीं भूल सकेंगे. रविवार की शाम जब कस्बे के लोग अपने घरों में टीवी पर हिंदी

फिल्म देख रहे थे उस समय अचानक ही सायरन के शोर ने सनसनी फैला दी. पता चला कि सायरन स्थानीय स्टेट बैंक का है. सायरन बजने का मतलब यही था कि चोरों ने बैंक में सेंध लगा ली है और वे खजाने वाले कमरे में घुस गए हैं.

बात की बात में खबर स्थानीय पुलिस थाने तक जा पहुंची और पुलिस ने बैंक के आसपास घेरा डाल दिया. इस दौरान सायरन लगातार बजता रहा और कस्बे के लोगों की उत्सुकता बढ़ाता रहा. बैंक का ताला खुलवाने के लिए जब मैनेजर के घर पर संपर्क किया गया तो पता चला कि साहब पास के एक और कस्बे में गए हुए हैं. पुलिस ने वायरलेस पर तुरंत वहां के थाने से संपर्क किया और मैनेजर साहब की खोज के लिए वहां भी दौड़धूप शुरू हो गई. इस बीच लगातार दो घंटे तक बजते रहने के बाद बैटरी ठंडी पड़ने के कारण सायरन भी चुप हो गया. देर रात मैनेजर साहब वहां पहुंचे और पुलिस के पहरे में ताला खोला गया. 'चोरों' की खोज के लिए बैंक का कोना-कोना छान मारा गया मगर एक चिड़िया भी हाथ नहीं लगी. बाद में जांच करने पर पता चला बिजली के शार्ट-सर्किट के कारण सायरन अचानक बजने लगा था.

वाह चोर जी!

■ चोरों की करतूतों के किस्से तो आए दिन सामने आते रहते हैं पर चोर बिरादरी के ईमानदार सदस्यों के कारनामे कभी-कभी ही सुनने को मिलते हैं. पिछले दिनों सहारनपुर के एक चोर ने अपनी समझदारी और ईमानदारी का जो उदाहरण पेश किया वह चोर बिरादरी की शान में चार चांद लगाने वाला है.

हुआ यह कि स्थानीय एचएवी इंटर कॉलेज के एक प्राध्यापक ने बाजार में एक दुकान के सामने साइकिल खड़ी की और कुछ कागज टाइप कराने के लिए दुकान में चले गए. बाहर आने पर यह देख वे धक से रह गए कि साइकिल। गायब थी और उसके साथ ही टोकरी में रखे बोर्ड की परीक्षा संबंधी कागजात भी. बेचारे बहुत परेशान हुए लेकिन चार दिन बाद ही डाक में आए एक पैकेट ने इस परेशानी को आधा कर दिया. पैकेट में कागजात का बंडल ज्यों का त्यों रखा हुआ था और उसके साथ टाइप की हुई एक चिट्ठी भी थी. चिट्ठी में चोर महोदय ने लिखा कि प्राध्यापक और विद्यार्थियों का नुकसान न हो इसलिए वह कागजात लौटा रहा है लेकिन साइकिल की सख्त जरूरत को देखते हुए उसने इसे अपने ही पास रखने का फैसला किया है. कागजात मिल जाने की खुशी से

भावविभोर प्राध्यापक ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज न कराने का फैसला किया है. उन्हें उम्मीद है कि इतना ईमानदार चोर जरूरत पूरी होने के बाद साइकिल भी लौटा देगा.

—संकलन: विजय क्रांति

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मेरे प्यारे भारत,

इस पखवाड़े कहने को इतना कुछ है कि समझ नहीं पा रहा हूं कि शुरू कहां से करूं. एक बजट पेश किया गया जिससे कोई मतलब नहीं निकला, एक पूर्व राष्ट्रपति ने कुछ कहा, विपक्ष ने भी वही राग दोहराया और सरकार है जो कहती जा रही है कि सब ठीकठाक है. अरे, मैं तो भूल ही गया कि एक प्रधानमंत्री भी हैं जो संसद में कहते हैं कि विपक्षी सदस्य जोकर हैं. उन्होंने एक सदस्य को 'ग्रूचो' तक कहा.

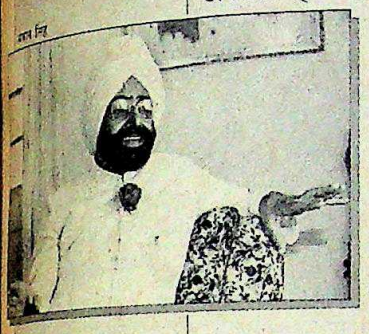

ज्ञैलसिंह ने साफ कर दिया कि उनकी जीवनी में अभी कुछ दिलचस्प अध्याय लिखे जाने हैं

पहले, घटनाओं का क्रमबद्ध ब्यौरा पहले तो पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह पखवाड़े का सबसे गरम मसाला लेकर आए. उन्होंने रहस्योद्घाटन किया कि उन्हें राष्ट्रपति का चुनाव दुबारा लड़ने के लिए 30-40 करोड़ रुपए तक की पेशकश की गई थी, शायद इस उम्मीद में कि एक गांधी का राजनैतिक जीवन बीच में ही खत्म हो जाए. इस गांधी और उनकी पार्टी वाले बड़े खुश हुए इस धोखे में कि जैल सिंह ने विपक्ष के कुछ लोगों को आखिर निशाना बना लिया. उन्होंने खुशी-खुशी एक जांच भी बिठा दी. लेकिन अफसोस कि तेजी से काम करने वाली सरकार ने फिर तेजी वहां दिखाई जहां थोड़ी सुस्ती बरतनी चाहिए थी.

मेनन पाकिस्तान जाने के लिए बोरिया-बिस्तर बांध ही रहे थे कि इस्लामाबाद ने मामला उलट दिया

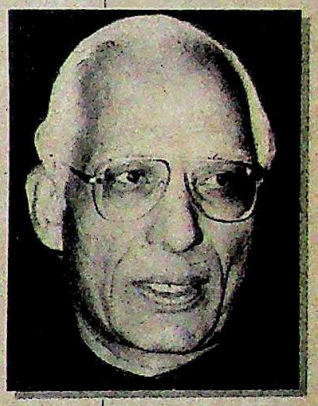

जैल सिंह ने यह कहकर उनके रंग में भंग डाल दिया कि घूस की पेशकश करने वालों में से कुछ लोग अभी भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में हैं. और इसके बाद सरकार और प्रचार माध्यमों के कुछ चेहरों को तमतमाया हुआ छोड़कर ज्ञानी जी चुप हो गए. बहरहाल, उन्होंने अपनी बात तो कह ही दी. उनकी जीवनी में अभी भी ऐसे दिलचस्प अध्याय हैं जिन्हें लिखा जाना है.

राजीव गांधी को एक और सदमा तब पहुंचा जब राष्ट्रपति जिया ने अफगान मसले पर बातचीत का उनका बुलावा नामंजूर कर दिया. जिया ने उलटे यह सुझाव दिया कि राजीव ही किसी को इस्लामाबाद भेज दें. दिल्ली ने अपने विदेश सचिव को भेजने का फैसला किया लेकिन वे बोरिया-बिस्तर बांध ही रहे थे कि खबर आई कि उसे तारीखें जंच नहीं रहीं.

पंजाब के मामले में हो रही ताजा कारिवाइयों के नतीजे खतरनाक भी हो सकते हैं

फिर पंजाब के मोर्चे पर लगा कि कुछ हो रहा है लेकिन सवाल यह है कि क्या हो रहा है और किस दिशा में हो रहा है. केंद्र सरकार ने आखिर सिख मुख्य ग्रंथियों और दूसरे कुछ कैदियों को जेलों से रिहा कर दिया. लेकिन इन तमाम प्रयासों के नतीजे खतरनाक भी हो सकते हैं. जिस व्यक्ति—जसबीर सिंह रोडे—पर सरकार ने इतनी ज्यादा उम्मीदें बांध रखी हैं वह भी अपने नामी चाचा जरनैल सिंह भिंडरांवाले की तरह आस्तीन का सांप साबित हो सकता है.

विपक्षी एकता के मोर्चे पर भी कुछ गतिविधियां रहीं लेकिन अजीबोगरीब दिशाओं में. बड़ी उलझनपूर्ण स्थिति है. कहना मुश्किल है कि जनता पार्टी का लोकदल (अ) में विलय हुआ या लोकदल (अ) का जनता पार्टी में. संजय मंच की तो याद है न? वह भी जनता पार्टी में मिल गया. और जनता पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर की तो याद होगी ही. उन्होंने अजीत सिंह को (उनकी याद नहीं होगी) को अपना उत्तराधिकारी बनाने के चक्कर में सब चौपट कर दिया. उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उनका मुखर विरोध किया है. लेकिन गैर-वामपंथी पार्टियों के नेताओं ने दिल्ली में रैली करके कुछ बहादुरी दिखाई. उन्होंने यथाशीघ्र राजीव सरकार को हटाने का संकल्प लिया है. है न जाना-पहचाना नारा!

प्रमोद पुष्करणा

विपक्ष ने राजीव सरकार को हटाने का वही रटा-रटाया संकल्प दोहराया

लेकिन तमिलनाडु के एक सांसद ने संसद में नोटों से भरी एक अटैची खोलकर जैसे उपरोक्त तमाम घटनाओं को फीका कर दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि ये नोट और कुछ दूसरे प्रलोभन उन्हें अन्नाद्रमुक के जयललिता गुट में शामिल होने के लिए दिए गए. उन्होंने कबूल किया कि वे मद्य प्रेमी रहे हैं फिर भी उन्होंने अपहरण, घूसखोरी, राजनैतिक खरीद-फरोख्त की शर्मनाक कहानी का भंडाफोड़ तो किया ही. बेचारे! मानो लोग विश्वास ही कर लेंगे कि ऐसी बातें सचमुच ही होती हैं.

तुम्हारा
दिलीप बॉब

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पंजाब

खतरनाक खेल शुरू

केंद्र सरकार एक साथ सख्त और लचीला रुख अपना रही है

पंजाब में करीब 150 लोगों की नृशंस हत्याओं के कारण यह पखवाड़ा सबसे खूनी और सनसनीखेज पखवाड़ों में से एक रहा. करीब तीन साल पहले राजीव-लोंगोवाल समझौते के बाद केंद्र ने सबसे महत्वपूर्ण कदम इसी पखवाड़े उठाया. उग्रवादी सिख ग्रंथियों और जोधपुर जेल के 40 नजरबंदियों की रिहाई से बातचीत का रास्ता फिर खुला है तो विधानसभा भंग किए जाने से पता चलता है कि केंद्र अकालियों को बीच में लाए बगैर उग्रवादियों से सीधे बातचीत का इच्छुक है. अमृतसर और चंडीगढ़ से विशेष संवाददाता ***शेखर गुप्ता*** *और वरिष्ठ संवाददाता* ***विपुल मुद्गल*** *की रिपोर्ट:*

स्वर्ण मंदिर में पिछले पखवाड़े बड़ी हस्तियां एकाएक फिर लौट आईं. भिंडरांवाले से मिलती-जुलती शक्ल-सूरत और रौब-दाब वाले जसबीर सिंह रोडे ने सिख राजनीति की धुरी थामकर सिख उग्रवाद के नए प्रवक्ता के बतौर अपनी स्थिति मजबूत कर ली. उनसे भी ज्यादा उग्र तेवर रखने वाले तीन मुख्यग्रंथी भी नई दिल्ली की तिहाड़ जेल से छूटने के बाद बने अपने नए प्रभामंडल में बिजली-से कौंध रहे हैं. लंबे-लंबे डग भरते हुए अकाल तखत का रास्ता तय कर रही इन हस्तियों के साथ एके-47 चीनी राइफलें, सब-मशीनगनें लिए तथा कमर में केसरिया दुपट्टों से रिवॉल्वरें बांधे और रह-रहकर 'राज करेगा खालसा' के नारे बुलंद करती खाड़कुओं की भीड़ बताती है कि इस सबका असली संदेश क्या है. यह संदेश उतना ही मुखर है जितना कि सिखों के ये नए नेता. लेकिन इक्का-दुक्का तेज आवाजों को छोड़कर किसी ने भी 'खालिस्तान' का नारा बुलंद नहीं किया है.

एक तरफ तनावग्रस्त राज्य में पुलिस आतंकवादियों से सबसे बड़ी लड़ाई में उलझी हुई है वहीं केंद्र ने बुरी तरह विभाजित आतंकवादी गुटों को एक करने और उनकी उम्मीदों को एकसूत्र करने में शायद सबसे ज्यादा सक्षम व्यक्ति को अमृतसर भेजने का फैसला कर लिया. सिख पंथ के सर्वोच्च राजनैतिक-धार्मिक आसन अकाल तखत के प्रमुख के पद पर रोडे के विराजमान होने के बाद केंद्र इस नाटक के अगले प्रकरण की बेचैनी से प्रतीक्षा कर रहा है.

1981 में पंजाब संकट उभरने के बाद में पहली बार केंद्र सरकार ने बीच के अकालियों से बातचीत चलाने के बजाय सीधे विभाजित आतंकवादियों तक पहुंच बनाने की कोशिश की है. विधानसभा भंग करने से यह संकेत मिलता है कि पंजाब के वर्तमान परिदृश्य में अकाली अब महत्वहीन हो चले हैं. निराश और हताश हो चुके केंद्र को पहली

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इसका महसूस हुआ कि उग्रवादियों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाने वालों की बजाय सीधे बंदूक उगलने वाली से ही लेनदेन की बातचीत शुरू करनी चाहिए.

पंजाब पर नई रणनीति तय करने वाले एक उच्चस्तरीय अधिकारी ने कहा, "बड़े दांव के लिए राजीव गांधी ने एक खतरनाक खेल शुरू कर दिया है." अलगाववादी आंदोलन के प्रति बढ़ते रुझान से हैरान और परेशान केंद्र ने एक साहसिक फैसला किया है. अब अपने पत्ते चल देने के बाद वह बेहतर और बदतर दोनों ही हालात का सामना करने के लिए सन्नद्ध हो रहा है.

अगर सब कुछ ठीकठाक चलता रहा तो रोडे को विभिन्न उग्रवादी गुटों को एक करने और कुछ हद तक उन पर अनुशासन तथा नियंत्रण रखने में कामयाब हो जाना चाहिए. नई दिल्ली को उम्मीद है कि जैसे ही कमान उनके (रोडे के) हाथ में आ जाएगी, वे शायद पंजाब को जम्मू-कश्मीर या नगालैंड की तरह का विशेष संवैधानिक दर्जा देने के मसले पर बातचीत के लिए तैयार हो जाएंगे. हालांकि रोडे ने कोई वायदे नहीं किए हैं और न ही कोई बातचीत ही की है पर अब तक उन्होंने जो कहा है, वह उत्साहवर्धक है (देखें बातचीत). पंजाब पुलिस के मुखिया जूलियो फ्रांसिस रिबेरो कहते हैं, "पंजाब में अमन वापसी के लिए हमें उन्हें खालिस्तान से कमतर कुछ भी देने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए." नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के एक वरिष्ठ सहयोगी ने कहा, "मुश्किल यह है कि पंजाब में कोई ललडेंगा नहीं है जिससे बात की जा सके."

अकाल तखत को जाते नए मुख्यग्रंथी: कमान हाथ में

सभी फोटो प्रशांत पंजियार

लेकिन रोडे को ललडेंगा बनाने की कोशिश करना बहुत खतरनाक है. इस बात की कोई गारंटी नहीं कि यह नया ललडेंगा तुरत-फुरत अमन की बात करने लगेगा. यदि रोडे खालिस्तान की मांग को अकाल तखत की मान्यता दे दें और अलगाव के सिवा किसी भी बात पर समझौता नहीं वाले उग्रपंथी विचारों से सहमत हो जाएं तो क्या होगा?

हालांकि सरकारी प्रवक्ता मानते हैं कि खतरा मोल लेना उचित है. पुलिस कार्रवाई तेज होने के बावजूद हत्याओं का सिलसिला और संख्या बढ़ी ही है; गांवों में सिख जनता में अलगाव की भावना बढ़ी है. और जैसे-जैसे मई में राष्ट्रपति शासन की अवधि के समाप्त होने का समय नजदीक आ रहा है वैसे-वैसे प्रधानमंत्री का धीरज भी टूट रहा है.

इसलिए जल्दी ही कुछ करने की जरूरत थी. केंद्र ने कुछ समय तक निगरानी के बाद रोडे के रूप में दांव खेलने का फैसला किया. जैन मुनि सुशील कुमार समेत केंद्र के कुछ मध्यस्थों की नजरबंद ग्रंथियों से कई दौर की बातचीत के बाद ही ये रिहाइयां हुईं. केंद्र से मुनि के ताल्लुकात के बारे में उग्रवादियों के प्रारंभिक भ्रम को दूर करने के लिए राजीव ने 10 फरवरी को शांतिदूत के रूप में मुनि की भूमिका की प्रशंसा कर डाली.

फिलहाल यह अनुमान लगाना कठिन है कि रोडे फायदेमंद साबित होंगे या एक और विपत्ति के कारण बनेंगे. लेकिन पिछले पखवाड़े अमृतसर में चली हवा का रुख बहुत ही धीमा और कभी भी रुक जाने के अंदेशे के बावजूद आशा बंधाता है. ताजपोशी के वक्त कई वर्तमान और पूर्व ग्रंथियों द्वारा केंद्र और 'हिंदू राज' के खिलाफ विषवमन किए जाने के बाद रोडे ने मंच संभाला और सिखों को "केंद्र के अत्याचारों का अपने सिद्धांतों और परंपरा के अनुरूप जवाब देने" के लिए प्रेरित किया. लेकिन उनके अपेक्षाकृत उदार स्वर से उनके समर्थक और कट्टरपंथी भी चकित रह गए.

खालिस्तान शब्द के इस्तेमाल से बचते हुए उन्होंने अपने भाषण में 'पूरन हक' के पक्ष में और हिंसा की निरर्थकता पर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जोर दिया, ठीक उसी तरह जैसे कि राजीव ने घोषणा की कि सरकार हिंसा छोड़ देने वालों से बातचीत करने को तैयार है. रोडे ने सिखों की स्वतंत्रता और गरिमा के लिए लंबे संघर्षों की भावना को उभारा लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कई चेतावनियां भी दीं: सिख जब तक एक नहीं होंगे तब तक वे जीत नहीं सकते और स्वर्ण मंदिर के भीतर अत्याचारों और जबरन रकम उगाही के आरोपों में कुछ सचाई है तो सिखों के आत्म-विश्लेषण का यही सही समय है.

रोडे ने हाल में हुए सभी सरबत खालसा के प्रस्तावों पर पुनर्विचार की भी घोषणा की. इनमें से एक सरबत खालसा में खालिस्तान मांगा गया था. इसके अलावा दूसरे उग्रवादियों की तरह रोडे ने संविधान को एकबारगी खारिज करने की घोषणा भी नहीं की. नए जत्थेदार ने 'भारतीय संविधान के भीतर या बाहर' सिखों की आजादी का समर्थन करते हुए कहा, "अगर भारतीय संविधान में सिखों के लिए सम्मानजनक स्थान है तो वे भी उसका आदर करेंगे."

साल भर पहले इनमें से कुछ बयान किसी सिख नेता को जेल में डालने के लिए काफी थे. लेकिन पंजाब का लगातार बदल रहा राजनैतिक परिदृश्य ऐसी विडंबनाओं को जगह देता है. आज ये वाक्य अपेक्षाकृत उदारवादी लगते हैं. रोडे के बयान जेल से छूटने के तुरंत बाद संत लोंगोवाल के बयानों से भी नरम हैं. हालांकि उन्हें यह रुख बनाए रखने में मुश्किल होगी.

उनकी ताजपोशी के बाद उग्रवादी खेमे के मूड से यह जाहिर हो गया है कि उन पर दबाव बहुत भारी है और बढ़ता ही जाएगा. उग्रवादियों द्वारा राजनैतिक मामलों में मुख्य-ग्रंथियों से बड़ी माने जाने वाली पांच सदस्यीय पंथक कमेटी के प्रमुख वक्ता तथा खालिस्तान कमांडो फोर्स के 'लेफ्टिनेंट जनरल' जागीर सिंह ने कहा, "सिखों के लिए जत्थेदार साहिब परिवार के एक बुजुर्ग के समान हैं. हम उन्हें पूरा आदर देंगे. और जब तक उनके आदेश सिख मर्यादा के अंदर हैं, हम उनका पूरा पालन करेंगे."

अखिल भारतीय सिख छात्र संघ के अधिक उग्र गुरजीत सिंह गुट के नेताओं का नजरिया इस बारे में ज्यादा साफ है. संघ के कार्यवाहक महासचिव गुरजीत सिंह 'काका' ने कहा, "जो भी आदेश वे हमें देंगे हम उसका

स्वर्ण मंदिर

आंदोलन का ज्वलंत प्रतीक

यह सिख आस्थाओं का वेटिकन, यरूशलम और मक्का सब कुछ है. लेकिन पिछले छह साल से स्वर्ण मंदिर अकाली आंदोलन और सिख उग्रवाद का भी प्रतीक बन गया है. सरकारी एजेंसियों का कहना है कि पंजाब में आतंकवाद का केंद्र यही है और इसके परिसर में हर तरह के घृणित अपराध होते हैं. उग्रवादियों के नेता इस आरोप का तो खंडन करते हैं पर इस हकीकत को नहीं छिपाते कि वे स्वर्ण मंदिर परिसर में हथियार लाते ले जाते हैं.

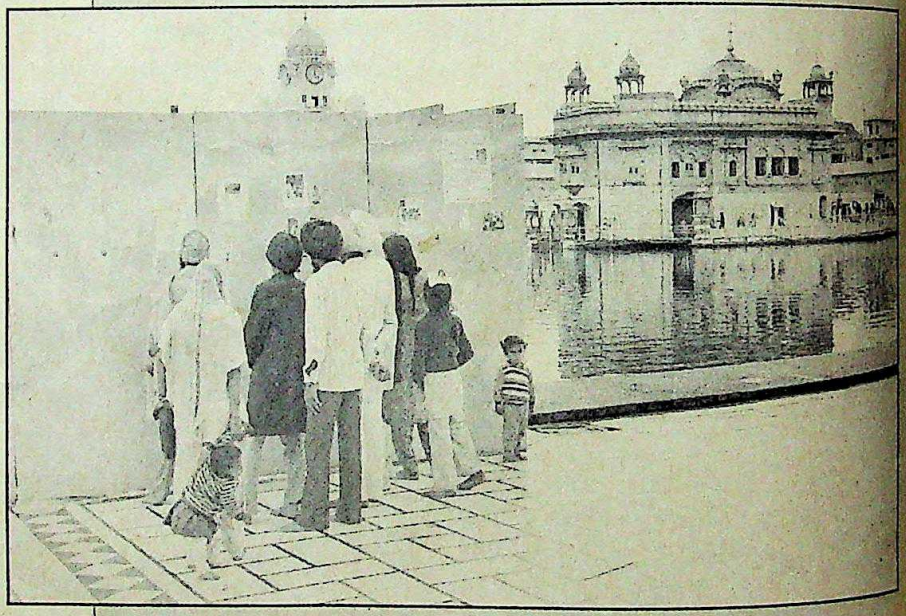

आतंकवादियों के पोस्टर पढ़ते श्रद्धालु

घातक हथियार तो उन दोनों कमरों में भी देखे जा सकते हैं जो फिलहाल मुख्य-ग्रंथियों के पास हैं. फोल्ड की जा सकने वाली एके-47 राइफलों से लैस पहरेदार मुख्यद्वार से उस कमरे तक की दिन-रात चौकसी करते हैं जहां अकाल तखत के नए जत्थेदार जसबीर सिंह रोडे रह रहे हैं. जब एक पहरेदार से पूछा गया कि उसकी एके-47 राइफल चीनी है या रूसी तो उसने शांत भाव से स्वर्ण मंदिर की ओर इशारा करते हुए कहा, "यह गुरु रामदास (स्वर्ण मंदिर के निर्माता) से पूछिए जिनकी कृपा से ये हथियार हमें मिले हैं."

पवित्र सरोवर की परिक्रमा करने पर नजर एक जगह अटक जाती है. सरोवर के दाईं तरफ फौलादी चादरों की एक दीवार सी खड़ी कर दी गई है. जिस पर उग्रवादी गुटों की सूचनाएं चिपकी हैं और मारे गए उग्रवादियों की तस्वीरों के साथ मुठभेड़ की खबरों की कतरनें लगी हैं. पिछले पखवाड़े सबसे चर्चित पोस्टर वह था जिसमें कुख्यात आतंकवादी हरजिंदर सिंह जिंदा की रिहाई मांगने के लिए पंजाब पुलिस की निंदा की गई थी. जिंदा अभी दिल्ली में बंद है.

इस दीवार के सामने परिक्रमा में कमरा नंबर 46, 47 और 48 हैं. खुफिया एजेंसियां इन्हीं कमरों को आतंकवादियों का मुख्यालय मानती हैं. पहले दो में ताले लगे हैं. 46 नंबर के दरवाजे पर पंजाबी में चेतावनी लिखी है: ताला तोड़ना मना है. 47 नंबर कमरे के दरवाजे पर 'इंडिया टुडे' का एक पुराना आवरण चिपका हुआ है जिस पर एके-47 राइफल लिए एक आतंकवादी का रेखाचित्र छपा है.

वरिष्ठ पुलिस अफसर कहते हैं कि यह उग्रवादियों का यातना केंद्र है. पिछले पखवाड़े पुलिस ने एक नकाबपोश सिख नौजवान को पत्रकारों के सामने पेश किया था. उसे कमरा नंबर 47 में इसलिए ले जाया गया क्योंकि उस पर पुलिस का

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मुखबिर होने का संदेह था. उसका दावा है कि उसके सामने एक और संदिग्ध मुखबिर को चाकू और आरी से छील दिया गया था. उसने बताया, "उन लोगों ने मुझसे कहा कि अगर गलती मान लूं तो गुरुग्रंथ साहिब की कसम वे मुझे दंड नहीं देंगे. वरना मेरा भी वही हश्र होगा." पर परिसर में रह रहे उग्रवादी नेता इस बात का जोरदार खंडन करते हैं. ऑल इंडिया सिख स्टुडेंट्स फेडरेशन (गुरजीत गुट) के महासचिव शेर सिंह कहते हैं, "हफ्ते भर साथ रहकर देखिए और फिर कहिए आपने कोई बलात्कार, जोर-जबरदस्ती या हत्या देखी है."

वे बगल के कमरा नंबर 48 में अपने उग्रवादी गुट के दूसरे साथियों के संग बैठते हैं. यहां की दीवारें उन लोगों की तस्वीरों से भरी हैं जो पुलिस के हाथों मारे गए हैं. दीवारों के साथ-साथ भिंडरांवाले और उसके साथियों के एकदम नए बनाए गए रेखाचित्र सुखाने के लिए रखे हैं. शेर सिंह कहते हैं, "हम यहां से किसी को ज़ोर-जबरदस्ती का कोई खत नहीं भेजते."

करीब 25 गज दूरी पर हथियार भी देखे जा सकते हैं. रामगढ़िया बंगा बुर्ज के नीचे राइफलें लिए कुछ लोग आराम कर रहे हैं. 18वीं सदी का यह बुर्ज ऑपरेशन ब्लूस्टार के दौरान तहस-नहस हो गया था. वे कैमरों की तरफ देखकर हंस पड़ते हैं पर कुछ पूछते नहीं.

बाकी की दो-तिहाई परिक्रमा में कोई असामान्य बात नहीं दिखी पर अचानक ही हथियार फिर नजर आने लगे. कमसिन लड़के अपनी पिस्तौलें छुपाने की कोई कोशिश नहीं करते. पर बड़े लोग इसका ख्याल रखते हैं. उनकी एके-47 राइफलें मोटे कंबल के नीचे छुपी रहती हैं. 27 डिग्री सेल्शियस की गर्म दुपहरी में भी वे कंबल ओढ़े रहते हैं.

अकाल तखत की इमारत के बगल वाले कमरा नंबर 14 और 15 में उग्रवादियों के नेता रहते हैं. वे अपनी नीयत और मकसद कुछ नहीं छुपाते. खालिस्तान कमांडो फोर्स के एक 'लेफ्टिनेंट जनरल' जागीर सिंह कहते हैं, "हम योद्धा हैं. लड़ाई चल रही है और लोग तो मारे ही जाएंगे." पुलिस के लिए वे 'बी-प्लस' श्रेणी के आतंकवादी हैं और उनके सिर पर 50,000 का इनाम है.

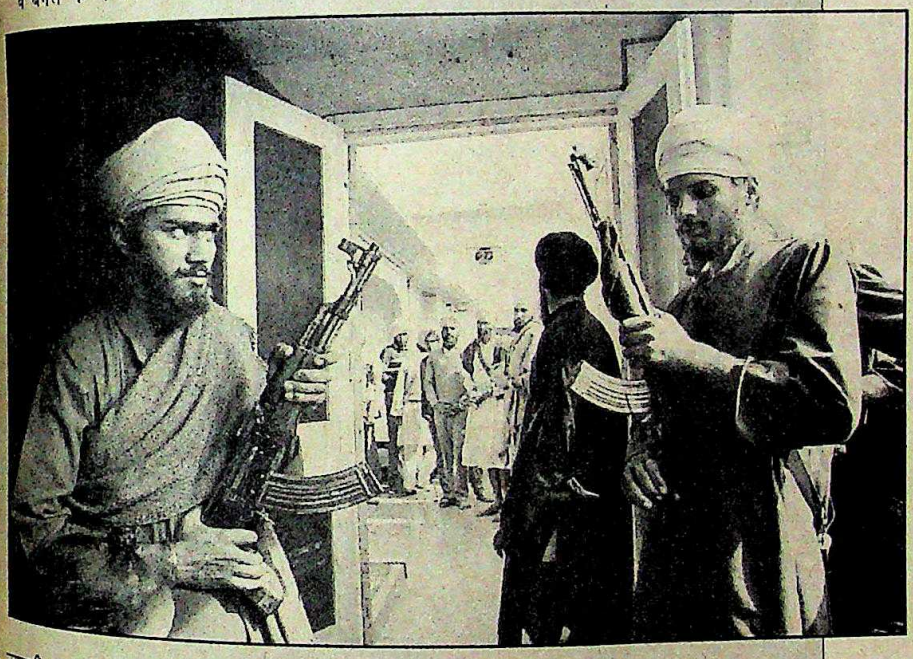

रोडे की हिफाजत करते बंदूकधारी

वहां पर उन जैसे अनेक लोग हैं. इसी कारण बहुत से पुलिस अफसर मांग करते हैं कि स्वर्ण मंदिर परिसर पर एक और हमला बोला जाना चाहिए. पर आला सतह पर सरकार की सोच पुराने तजुर्बों की वजह से संयम बरतने वाली हो गई है. परिसर पर जब भी छापा मारा गया, आतंकवाद मजबूत ही हुआ. उदार सिखों की निगाह में आतंकवादियों के लिए हमदर्दी ही बढ़ी. सबसे बड़ी बात यह है कि स्वर्ण मंदिर का रहस्य और गहरा बनकर धार्मिक चुनौती का प्रतीक बन गया.

—शेखर गुप्ता

गुलदस्तों से स्वागत करेंगे."

वक्त बीतने और उन्माद की जगह सही राजनैतिक हालत लौटने के साथ इन्हीं आकांक्षाओं के कारण रोडे को केंद्र से भी अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा. इस तरह उन्हें ज्यादा लड़ाकू रुख अख्तियार करना होगा. असल में खाड़कुओं में ग्रंथियों की रिहाई के बाद हत्याओं की संख्या घट जाने की धारणा से पहले ही खलबली मची हुई है. जागीर सिंह ने कहा, "ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है. जल्दी ही और अधिक लोग मर सकते हैं. लेकिन हर रोज एक जैसी संख्या में तो लोग नहीं मारे जा सकते. यह मामला ऐसा नहीं कि आपको हर रोज दो चपातियों का एक बंधा-बंधाया भोजन ही करना पड़े."

अपने चारों तरफ लड़ने-भिड़ने के इस वातावरण में रोडे को इस परोक्ष आक्षेप को भी ध्यान में रखना होगा कि उन्हें केंद्र से एक गुप्त समझौते के तहत रिहा किया गया है. उन्होंने बमुश्किल इसका खंडन किया है. आज के वातावरण में यह ऐसा तथ्य है कि किसी सिख नेता की राजनीति एक झटके के साथ खत्म कर सकता है. रोडे के समर्थक तथा सिख छात्र संघ (गुरजीत गुट) के फिरोजपुर जिले के अध्यक्ष 36 वर्षीय जसमेल सिंह पांधीजट्टां ने कहा, "कोई भी पीठ पीछे केंद्र से गुप्त समझौता नहीं करेगा. लोंगोवाल की क्या नियति हुई. यह किसी को भूलना नहीं चाहिए."

सरकार के कट्टरतम आलोचक भी पंजाब में राजनैतिक पहल की अनिवार्य जरूरत को नहीं नकारते. लेकिन सरकार के भीतरी लोगों के साथ ही बहुतेरे दूसरे लोग इसके लिए चुने गए समय के चुनाव पर सवाल जरूर उठाते हैं. नई दिल्ली और चंडीगढ़ के कुछ उच्चस्तरीय सूत्रों ने इस बात की ताईद की कि राय और रिबेरो दोनों ने ही पिछले नवंबर में जब सुरक्षा बल उग्रवादियों पर हावी थे तब केंद्र से उग्रवादियों से बातचीत चलाने की पहल करनें को कहा था. तब पूछताछ और मुठभेंड़ों के क्रूर पुलिसिया तरीकों से खाड़कुओं के मन में कुछ हद तक खौफ बैठ गया था.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कहते हैं, "खुफिया विभाग के लोग ऐसी सूचनाएं ला रहे थे कि कुछ उग्रवादी निबटारे के मूड में हैं और यह खबर दिल्ली को बता दी गई थी." राय, रिबेरो, राजीव और केंद्रीय गृहमंत्री बूटा सिंह के बीच कई घंटों की बातचीत के

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बाद इस तनावग्रस्त राज्य के लिए कुछ महत्वपूर्ण राजनैतिक-आर्थिक रियायतें देने का फैसला किया गया था.

लेकिन केंद्र यह जाने बगैर यह सब नहीं करना चाहता था कि कम-से-कम उग्रवादियों का एक हिस्सा इसके प्रति सही रुख अपनाने को तैयार है. पर अपनी गतिविधियों के बाद जैन मुनि सुशील कुमार ने केंद्र को ऐसा ही आश्वासन दिया. इस तरह पहल का रास्ता खुला, लेकिन दुर्भाग्यवश यह होते-होते दो महीने लग गए और तब तक पुलिस पर आतंकवादी हावी होते दिखने लगे.

अब जब मामला तय हो गया तो केंद्र खाड़कुओं की तरफ से सकारात्मक संकेत मिलने का इंतजार कर रहा है. अगर ऐसे संकेत मिले तो और कई रियायतें दी जाएंगी. उच्चस्तरीय सूत्रों के मुताबिक इनमें निम्न-लिखित रियायतें शामिल हैं:

- ► कट्टर माने जाने वाले सौ बंदियों को छोड़कर जोधपुर में बंद दूसरे लोगों की जल्द से जल्द रिहाई.
- ► सीमावर्ती इलाकों में रोजगार मुहैया कराने के लिए लंबी अवधि की आर्थिक योजनाएं शुरू करना.
- ► राज्य में पेप्सी कोला सहित 1900 करोड़ रुपए लागत का पेट्रोकेमिकल प्लांट, कई चीनी मिलें और कई कृषि आधारित उद्योग-धंधे लगाना.

कुल मिलाकर राज्य के संवेदनशील सीमावर्ती इलाकों में कम-से-कम 25,000 नौकरियां पैदा करने की योजना की उम्मीद है. वर्तमान वातावरण में ये रियायतें काफी काम की साबित होंगी.

अब तक केंद्र और उग्रवादियों के बीच बने हुए तथाकथित उदार अकाली नेतृत्व को विधानसभा भंग कर पूरी तरह खारिज कर दिया गया है. पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और पूर्व कृषिमंत्री अमरिंदर सिंह रोडे की ताजपोशी के समारोह में शामिल हुए, शिरोमणि गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने तावड़-तोड़ उन्हें नया जत्थेदार कबूल किया और बरनाला गुट के नेताओं की तो स्वर्ण मंदिर में मौजूद होने की हिम्मत भी नहीं हुई.

उदारवादी सिख नेतृत्व से मोहभंग की स्थिति किसी और में नहीं बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल में ही मूर्त रूप में देखी जा सकती है. पहले उनकी रिहाई को उदारवादी विचारधारा की पुनर्प्रतिष्ठा माना जा रहा था. लेकिन हुआ ठीक उलटा ही. बादल उग्रवादियों द्वारा किया गया अपना

जसबीर सिंह रोडे

'राजीव अब समझदारी दिखाएं'

वही नैन-नक्श, वही चाल-ढाल, आंखों में वैसी ही चमक और उसी तरह की तीखी नाक. जसबीर सिंह रोडे और उनके दिवंगत चाचा जरनैल सिंह भिंडरांवाले में समानताओं को नजरअंदाज कर पाना बहुत मुश्किल है. यहां तक कि उम्र भी वही 34 साल, जिस उम्र में उनके चाचा ने स्वर्ण मंदिर में प्रवेश किया था और उथल-पुथल भरे कुछ ही महीनों में सिख राजनीति के सारे समीकरणों को बदल दिया था. अकाल तखत के नवनियुक्त मुख्यग्रंथी जसबीर सिंह रोडे भी भिंडरांवाले की तरह ही जेल से रिहाई के बाद मशहूर हुए हैं.

पर दोनों में फर्क भी हैं. रोडे में न भिंडरांवाले जैसा तौर-तरीका है, न वैसा दंभ. पर उनका अतीत उनके उदार मुखौटे को नकारता है. 17 साल की उम्र में वे रूढ़िवादी सिख पाठशाला दमदमी टकसाल में धार्मिक दीक्षा के लिए दाखिल हुए लेकिन रहस्यमय ढंग से दुबई खिसक गए. उनका नाम सुर्खियों में उस समय आया जब ऑपरेशन ब्लूस्टार के बाद वे अचानक पाकिस्तान में प्रकट हुए और वहां सिख तीर्थयात्रियों के सामने उन्होंने भड़काने वाले भारत विरोधी भाषण दिए. जैसे ही वे इस द्वीप से बाहर निकले खुफिया एजेंसियों ने उनका पीछा किया. लंदन पहुंचकर उन्होंने उग्रवादी अंतरराष्ट्रीय सिख यूथ फेडरेशन बनाई और शरण की खोज में वहां से निकल पड़े. थाइलैंड और फिलीपीन में नाटकीय अंदाज से पीछा करते हुए भारतीय एजेंटों ने उन्हें मनीला में धर दबोचा. अगले दो साल उन्होंने मध्य प्रदेश की सागर जेल में गुजारे और पिछले पखवाड़े रिहा कर दिए गए.

वक्त ही बताएगा कि वे भिंडरांवाले की तरह सिख संगतों पर अपना रंग जमा पाएंगे या नहीं. रिहाई के बाद पहली बार उन्होंने विशेष संवाददाता शेखर गुप्ता से ही बातचीत की. हिचकिचाते हुए उन्होंने कहा भी, "दरअसल मुझे बोलना नहीं चाहिए. मैंने तो अभी बीबीसी वालों से भी बात नहीं की है." बातचीत के कुछ अंश:

● पंजाब के हालात क्या इतने खराब हो चुके हैं कि उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं या आपको अभी कोई उम्मीद है?

हालात बुरी तरह बिगड़ चुके हैं [illegible] राजीव सरकार चाहे तो अभी भी [illegible] किया जा सकता है. उम्मीदें तो [illegible] कभी छोड़ी नहीं. हम जानते हैं [illegible] जीत तक कैसे लड़ते जाना है.

● तो हालात सुधारने के लिए [illegible] कर सकता है? आपकी और जोधपुर [illegible] बंदियों की रिहाई क्या शुभ संकेत [illegible]

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तिरस्कार भुलाते हुए ताबड़तोड़ उनके रथ पर चढ़ने को आतुर दिखते हैं. उग्रवादियों की कुछ सभाओं में तो उन्हें पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया. पर कई जगह वे फर्जी मुठभेड़ों के बारे में खाड़कुओं से भी बढ़-चढ़कर बोले.

लेकिन उग्रवादियों को फुसलाने के अपने तमाम प्रयासों के बावजूद बादल पंजाब की वर्तमान राजनीति में अपनी वैसी साख जमाने और सुरक्षा पाने में नाकाम रहे हैं. पंजाब पुलिस की सुरक्षा का भरोसा न करते हुए उन्होंने अपने करीबी दोस्त—मुख्यमंत्री देवीलाल के मार्फत अपने लिए हरियाणा पुलिस का एक विशेष गार्ड ले लिया है.

स्वर्ण मंदिर परिक्रमा से अकाल तखत की ओर तेज-तेज कदमों से चलते रौडे का विनीत भाव से अनुकरण करके और संगत में उनके पीछे बैठकर बादल ने अपनी परेशानी खुद ही

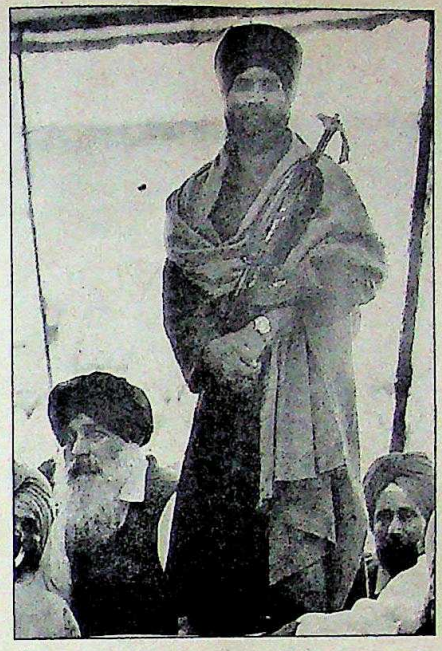

अकाल तखत पर बादलः उपेक्षित

उजागर कर दी है. और मजेदार बात यह है कि यह भी उस दशा में जबकि रौडे ने उनके खिलाफ तनखैया संबंधी हुकमनामा उठाने का कोई वायदा भी नहीं किया. बादल हालांकि खुद नहीं मानते कि वे अप्रासंगिक हो गए हैं. वे कहते हैं, "अकाल तखत के मुख्यग्रंथी का पद एक धार्मिक पद है." लेकिन पंजाब की हालत सुधारने के लिए पूछे गए साधारण से सवाल का भी जवाब देने से वे कन्नी काट जाते हैं. वे कहते हैं, "हम कर ही क्या सकते हैं? सिर्फ प्रार्थना ही तो कर सकते हैं."

बादल तो प्रार्थना में लगे हैं पर केंद्र को एक और महत्वपूर्ण फैसला करना है. उसे पुलिस कार्रवाई की सही दिशा अब तय करनी है. सरकार ने संसद और अनौपचारिक सलाह-मशविरों के दौरान स्पष्ट कर दिया है कि वह पुलिस कार्रवाई का विकल्प छोड़ने नहीं जा रही. दरअसल सरकार तो पंजाब की मौजूदा 'तनावग्रस्त स्थिति' के मद्देनजर वहां आतंरिक इमरजेंसी लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करने का मन बना चुकी है. समझा जाता है कि सरकार पंजाब की खबरें देने के मामले में राष्ट्रीय और अंतर-राष्ट्रीय समाचार माध्यमों पर कुछ बंदिश लगाने पर भी गौर कर रही है.

इससे पुलिस की आक्रामकता और बढ़ सकती है. रिबेरो कहते हैं, "अगर यह (राजनैतिक) पहल सफल हो जाती है तब भी पुलिस कार्रवाई बंद नहीं की जाएगी." दूसरी तरफ राय इसे 'एक हाथ में लड्डू और दूसरे में डंडा' जैसी पहल भी नहीं कहना चाहते. वे सिर्फ इतना कहने को ही तैयार हैं, "यह सही पहल है." वे कहते हैं कि तमाम अफवाहों के बावजूद न तो वे हटे रहे हैं और न ही रिबेरो मई में अवकाश ले रहे हैं.

स्पष्ट है कि सरकार रियायतें देने के बावजूद पुलिस कार्रवाई का रास्ता छोड़ने नहीं जा रही, ठीक उसी तरह जैसे खाड़कू भी हत्याएं बंद करने नहीं जा रहे. वक्त बदलने के साथ समस्या क्या रूप लेती है इसी से तय होगा कि सरकार कितना लचीला या कड़ा रुख अपनाएगी. लेकिन यदि इस पहल से उपजी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है तो पंजाब फिर खौफनाक खूरेजी और तनाव के दुष्चक्र में उलझ जाएगा जिसका नतीजा होगा— राज्य के गांवों में सेना की वापसी. और कोई भी यह नजारा फिर नहीं देखना चाहेगा— न तो केंद्र सरकार, न सेना, न खाड़कू और न ही परेशानहाल पंजाबी जनता.

रौडेः दृढ़ रवैया

सारी बात सरकार के हाथ में ही है. उसने एक तरह से शुरुआत की है. पर कितनी? बहुत थोड़ी-सी. रिहाई सिखों के लिए कोई बड़ी इनायत नहीं है. कुल मिलाकर इसका मतलब इतना भर है कि भारत सरकार ने अपनी कुछ गलतियां मानकर उन्हें ठीक कर लिया है.

• उग्रवादी कह रहे हैं कि केंद्र से बात मुमकिन है. आपका क्या ख्याल है?

अगर राजीव हमसे समझदारी से बात-चीत करें तो हम भी उनसे और उनकी सरकार से बातचीत कर सकते हैं.

• कुछ लोग मानते हैं कि सरकार ने पर्दे के पीछे हुए किसी समझौते के बाद आपको रिहा किया है. सचाई क्या है?

सचाई यह है कि हमारी रिहाई बिना शर्त हुई. मैंने धर्म का आचरण और शिक्षाएं दमदमी टकसाल के तीन महान जत्थेदारों से ग्रहण की हैं. वीरता से लड़कर सरकार को करारा जवाब देने वाले सिखों की कीमत लगाने वाला मैं आखिरी व्यक्ति होऊंगा.

• क्या बेगुनाह हिंदुओं के मारे जाने पर आपके मन में भी दर्द उठता है? इसका जिम्मेदार कौन है?

सिख सांप्रदायिकता में विश्वास नहीं करते. न वे निहत्थों-बेगुनाहों को मारते हैं. हम गुरु की इस दिशा को मानते हैं 'मानस की जात सभै एक ही पहिचानिबो'. फिर दूसरे फिरके के लोगों की हत्या का आरोप कैसे लगाया जा सकता है.

• क्या आपको नहीं लगता कि पंजाब में हिंदू और सिखों में दरार पैदा हो गई है? उनके रिश्ते तो बहुत प्रगाढ़ थे.

यह सवाल तो आपको सरकार से पूछना चाहिए जिसने इसकी शुरुआत की. हम सद्भावना बहाल करना चाहते हैं. पर मैं एक बात साफ कर दूं कि सिख हिंदू नहीं हैं. हम एक अलग कौम हैं.

• अधिकांश उग्रवादी संगठन खालिस्तान मांगते हैं और आप पूरी आजादी की बात करते हैं. फर्क क्या है?

यह इस बहस का वक्त नहीं है. इस पर हम बाद में कुछ कहेंगे.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ज्ञानी जैल सिंह

फिर विवाद का बवंडर

पर रहस्योद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति के लिए मुसीबत बन सकता है

भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए कितना पैसा चाहिए? 30 से 40 करोड़ रुपए के बीच. यह जवाब है भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह का. पदमुक्त होने से लेकर लगभग आठ महीने तक गुमनामी में रहने के बाद अब वे फिर से विवादों के घेरे में आ खड़े हुए हैं.

एक भेंटवार्ता में उन्होंने यह कहकर राजनैतिक क्षेत्रों में उथल-पुथल मचा दी कि सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ राष्ट्रपति पद के चुनाव में खड़ा होने के लिए उन्हें 30 करोड़ रुपए से अधिक धन उपलब्ध कराए जाने का वायदा किया गया था. लेकिन इस बयान से आगे किसी भी तरह का विवरण न देकर उन्होंने न केवल विरोधी दलों में बल्कि सत्ताधारी इंका के भीतर भी अच्छा-खासा बवाल खड़ा कर दिया है. लेकिन यह पहला मौका नहीं जब ज्ञानी जी ने लोगों को असमंजस में छोड़ा है. लोग इस सवाल पर तिकड़में भिड़ाने में लगे हुए हैं कि ज्ञानी जी असल में करना क्या चाहते हैं और उनका इशारा किन लोगों की ओर है.

इस मामले में हास्यास्पद बात तो यह है कि कलकत्ता के जिस साप्ताहिक ने यह भेंटवार्ता छापी उसने ज्ञानी जी की इस टिप्पणी को भेंटवार्ता के आखिरी चौथे पन्ने पर निहायत मामूली स्थान दिया. इससे भी ज्यादा हास्यास्पद बात यह रही कि इस सनसनीखेज खबर को सबसे पहले दूरदर्शन ने उछाला जो कि खबरों के बारे में अपनी नासमझी के लिए खासा जाना-पहचाना नाम बन चुका है. लेकिन यह खबर उछालने के पीछे दूरदर्शन का असली इरादा इस नजरिये का प्रचार करना था कि पूर्व राष्ट्रपति का इशारा जिन लोगों की ओर है वे अब सरकार से बाहर हो चुके हैं.

इसी नजरिये का प्रदर्शन अगली सुबह संसद में देखने को मिला जहां सत्ताधारी दल के सदस्यों ने इसे धूमधाम के साथ उछाला. इंकाई नेता इस खबर से यही मानकर चल रहे थे कि ज्ञानी जी ने यह बात उन लोगों के बारे में कही है जिन्होंने पिछले साल जुलाई में राजीव के खिलाफ बगावत का झंडा उठाया था. सरकार समर्थक अखबारों ने भी अपनी संपादकीय टिप्पणियों में दावा कर डाला कि उनके अंदाज बिलकुल सही सिद्ध हो रहे हैं.

उधर प्रधानमंत्री ने भी संसद में विरोधी पक्ष पर धुआंधार हमला करते हुए घोषणा कर डाली कि ज्ञानी जी का इशारा उन लोगों की ओर है जो अब इंका में नहीं हैं. ज्ञानी जी की इस टिप्पणी से ज्यादा से ज्यादा राजनैतिक लाभ उठाने के चक्कर में राजीव ने उनकी तारीफ में ऐसे कसीदे पढ़ डाले जिनकी कल्पना पिछले साल उन दिनों नहीं की जा सकती थी जब पूरा सत्ताधारी दल ज्ञानी जी के पीछे हाथ धो कर पड़ा हुआ था. यहां तक कि राजीव ने जैल सिंह को उनके 'साहसिक और नैतिक' कदम के लिए बधाइयां तक दे डालीं. राजीव ने लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ के सुझाव से सहमति दिखाते हुए गृहमंत्री बूटा सिंह को भी निर्देश दे दिया कि मामले की सचाई जानने के लिए तुरंत इन आरोपों की जांच करवाई जाए.

और दो दिन के बाद होली के अवसर पर ज्ञानी जी को शुभकामनाएं देने के लिए उनके घर जाकर राजीव ने सबको अचंभे में डाल दिया. जुलाई 1987 में ज्ञानी जी के रिटायर होने के बाद यह अपनी तरह की पहली घटना

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पर इस पर चुटकी लेते हुए पूर्व राष्ट्रपति के एक सहायक की टिप्पणी थी, "प्रधानमंत्री को दीवाली या गुरुनानक जन्म दिवस पर तो ऐसी बात नहीं सूझी थी पर अब शायद वे इसलिए आए कि मौके का ज्यादा से ज्यादा राजनैतिक लाभ उठाया जा सके."

केंद्रीय उद्योगमंत्री जे. वेंगलराव ने तो यहां तक आरोप लगा डाला कि इतना अधिक झूठ बोलना तो केवल आंध्र के मुख्यमंत्री एन. टी. रामाराव जैसे व्यक्ति के ही बस की बात है. उधर विरोधी पक्ष भी यह दावा कर रहा था कि जैल सिंह का असली इशारा सत्ताधारी दल की ओर है. राज्यसभा में तेलुगु देशम के नेता पी. उपेंद्र का कहना था, "यह बिलकुल स्पष्ट है कि पूर्व राष्ट्रपति ने पैसा वसूल करने का आरोप कांग्रेसी मंत्रियों पर लगाया है. सिर्फ वही लोग इतनी बड़ी राशि वसूल कर सकते हैं जो रक्षा सौदों के घोटालों में कमीशन खाते हैं."

मगर यह सारा मामला तब अचानक ही उलटा पड़ गया जब जैल सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि उनका इशारा उन लोगों की ओर भी है जो अभी सत्ताधारी दल में हैं. और भ्रम खड़ा करने के तुरंत बाद ज्ञानी जी ने इन लोगों के नामों के बारे में चुप्पी साध ली.

मजेदार बात यह रही कि इस सारे गुल-गपाड़े ने सबसे अधिक चकित स्वयं ज्ञानी जी को ही किया. 'इंडिया टुडे' से अपनी बातचीत में उनका कहना था, "मुझे नहीं मालूम था कि इस सबसे इतना बवाल खड़ा हो जाएगा, मेरी अनौपचारिक बातचीत को खामख्वाह राजनैतिक स्वार्थों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. मुझ पर दबाव डाले जा रहे हैं कि मैं इस या उस पक्ष के किसी व्यक्ति का नाम बताऊं. लेकिन मैं इस दबाव में आने वाला नहीं. उन दिनों तो पूरा माहौल ही गरम था. अधिकांश मंत्री और सांसद प्रधानमंत्री से नाराज थे और उन्हें हटाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे. कुछ लोग तो करोड़ों की बातें कर रहे थे. लेकिन ज्यों ही पैसे का सवाल खड़ा हुआ त्यों ही मैंने इस विचार को अस्वीकार कर दिया. समझ नहीं आ रहा कि आखिर सत्ताधारी दल इस बारे में इतनी गंभीरता क्यों दिखा रहा है."

राष्ट्रपति रह चुका और राजनीति का यह मंजा हुआ खिलाड़ी घटनाओं के केंद्र में आ जाने के बाद वहां से आसानी से हटने को तैयार नहीं होगा. अब वे ऐसी हालत में आ गए हैं जहां से सत्ताधारी और विरोधी पक्ष को डराए रख सकते हैं. उनका एक शब्द भी सत्ताधारी दल में कइयों की बरबादी का पैगाम सिद्ध हो सकता है. लेकिन फिलहाल ज्ञानी जी ने अपने तुरुप के पत्ते छिपाए रखने और प्रेस को किसी तरह की भेंटवार्ताएं न देने का पक्का फैसला कर लिया है. उनके निकटवर्ती सूत्रों का कहना है कि ज्ञानी जी राजीव को एक पत्र लिखने जा रहे हैं जिसमें आश्वासन मांगा जाएगा कि गृह मंत्रालय की जांच से पहले उन मंत्रियों बरखास्त कर दिया जाए जिनके नाम वे लेंगे. लेकिन इन सलाहकारों ने ज्ञानी जी को सलाह दी है कि अभी वे ऐसा कोई पत्र न भेजें.

इस बीच सरकार संसदीय जांच का हुक्म जारी करने के बाद अपने ही फेंके हुए जाल में फंस गई दिखती है. अब उसके लिए यह जांच रद्द करना बहुत भारी पड़ेगा. इसलिए अब मुसीबत से बचने के लिए एक ऐसे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री को मामला संभालने की जिम्मेदारी दी गई है जो ज़ैल सिंह के कट्टर विरोधी हैं. इससे पहले कि जैल सिंह किसी नाम से परदा हटाएं, उनके पास अनौपचारिक गपशप के नाम पर कुछ पत्रकारों और सांसदों को भेजने का फैसला किया गया. यह रणनीति कामयाब रही और ज्ञानी जी ने हालांकि खुद तो कोई नाम नहीं बताए लेकिन उन्होंने उन नामों को भी नहीं नकारा जिनका सुझाव पत्रकारों या राजनीतिकों ने दिया.

पूरे मामले में भ्रम पैदा करने की प्रमुख भूमिका मीडिया के एक वर्ग ने निभाई. जैल सिंह ने मिलने आए पत्रकारों को स्पष्ट कर दिया था कि वे अब कोई इंटरव्यू नहीं देंगे. लेकिन सरकार का समर्थन करने वाले कलकत्ता के एक साप्ताहिक ने इस अनौपचारिक बातचीत को एक विशुद्ध इंटरव्यू के रूप में प्रकाशित कर दिया. प्रकाशन से दस दिन पहले ही पीटीआई को इस 'टेप किए हुए' इंटरव्यू की लिखित पांडुलिपि थमा दी गई. लेकिन इस पत्रिका के सहयोगी दैनिक 'द टेलीग्राफ' ने पीटीआई से पहले ही इस 'इंटरव्यू' को प्रकाशित कर दिया.

लेकिन पूर्व राष्ट्रपति का कहना है कि उन्होंने किसी भी पत्र को इंटरव्यू नहीं दिया है. यहां तक कि उन्होंने कलकत्ता के साप्ताहिक के मालिक को बुलाकर उसे बता दिया कि यदि पत्रिका ने इंटरव्यू प्रकाशित किया तो वे उस पर मुकदमा दायर कर देंगे. ज्ञानी जी ने घोषणा की. "मैंने उन्हें अपने यहां अनौपचारिक बातचीत के लिए आने की इजाजत दी थी. यदि कोई मुझसे इंटरव्यू लेने

कार्टून: अजीत नायनन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

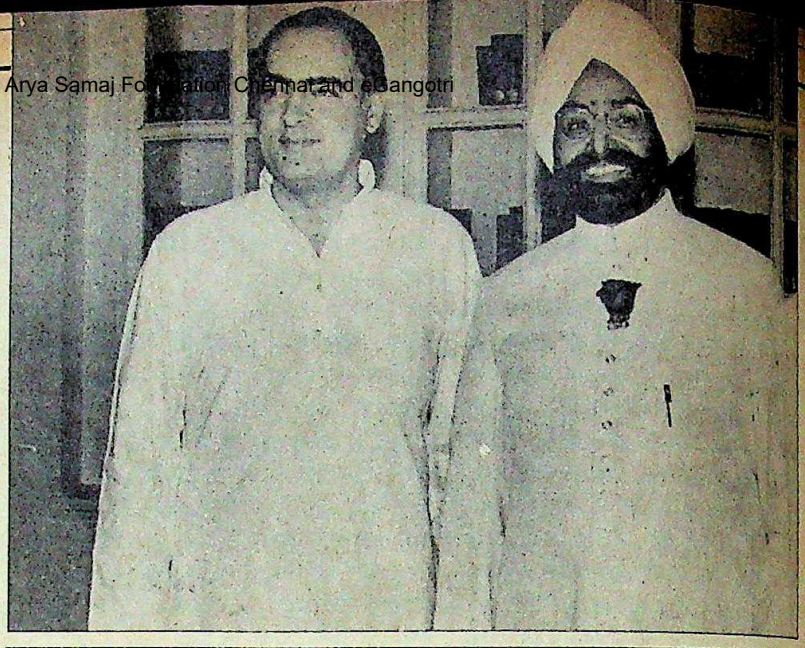

राजीव ने जैल सिंह को उनके इस 'साहसिक और नैतिक' कदम के लिए बधाई तक दे डाली. दो दिन बाद वे होली की शुभकामनाएं देने ज्ञानी जी के घर भी गए

का दावा कर रहा है तो मेरे ख्याल में यह षडयंत्र और धोखाधड़ी का मामला है." उधर साप्ताहिक का दावा है कि उसके पास इंटरव्यू का कैसेट मौजूद है.

अखबारों में परस्पर विरोधी रिपोर्टों ने जैल सिंह के इस सनसनीखेज रहस्योद्घाटन को और भी पेचीदा बना दिया है. सभी क्षेत्रों में इस बात पर अटकलें लगाई जा रही हैं कि इतना बड़ा धन देने की व्यवस्था कौन कर सकता है. इंका के सूत्र इस बारे में विद्याचरण शुक्ल, नंदमूरि तारक रामराव के नाम ले रहे हैं. विपक्ष में जिन नामों की चर्चा है उनमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह, वित्तमंत्री नारायणदत्त तिवारी, पी.वी. नरसिंह राव, और भजनलाल तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री गुरुदयाल सिंह ढिल्लों और प्रणव मुकर्जी शामिल हैं. युवा इंकाइयों का दावा है कि ज्ञानी जी को दुबारा चुनाव लड़ने के लिए उकसाने वालों में पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र, माधव सिंह सोलंकी और वसंत दादा पाटील जैसे असंतुष्ट और बुजुर्ग नेताओं का हाथ था.

इस तरह इस विवाद ने लोगों का ध्यान फिर उस राजनीति की ओर खींच लिया है जो जैल सिंह के राष्ट्रपति काल के अंतिम 6 महीनों में परदे के पीछे चली. यह वह दौर था जब विरोधी पक्ष के कुछ नेताओं और सत्ताधारी पक्ष के कुछ लोगों ने राष्ट्रपति को राजी कर लिया था कि प्रधानमंत्री को बरखास्त करके एक कार्यवाहक सरकार का गठन किया जाए. जैल सिंह को दो संभावित कार्यवाहक प्रधानमंत्रियों—आर. वेंकटरामन और नरसिंह राव के नाम भी सुझाए गए थे.

लेकिन यह देखते हुए कि खुलकर उनका साथ देने वाले सांसदों की संख्या बहुत प्रभावशाली नहीं है, जैल सिंह ने राजनैतिक होशियारी दिखाते हुए इस विचार को त्याग दिया था. वैसे भी विपक्ष द्वारा राजीव सरकार को पलटने के सुझावों को वी.पी. सिंह भी ठुकराने लगे थे. जैल सिंह के रिटायर होने के साथ ही यह संवैधानिक संकट भी अपने आप ठप हो गया. अब नौ महीने बाद संसदीय जांच का सवाल उठने से राजीव ने फिर से आफत मोल ले ली है.

मगर ऐसी जांच के बावजूद जो सवाल अनुत्तरित रहने वाला है वह यह कि आखिर ज्ञानी जी की चाल है क्या? जवाब केवल जैल सिंह की चरित्रगत विशेषताओं से ही मिल सकता है. राष्ट्रपति होते हुए भी उन्हें राजनीति से प्यार बना रहा. जितना मजा उन्हें पत्रकारों और राजनीतिकों के साथ गपबाजी करने में आता था उतना किसी और चीज में नहीं. वे अक्सर असावधानी में कई बातें कहते आए हैं लेकिन पत्रकार उन सब बातों को छापने से बचते रहे हैं. पर अब जबकि वे राष्ट्रपति नहीं रहे, पत्रकारों को ऐसी कोई बंदिश आड़े नहीं आएगी.

यह भी हो सकता है कि जैल सिंह ने स्वयं को अलग-थलग मानकर तथा परेशान होकर राजनैतिक खेल में लौटने के लिए यह इंटरव्यू दाग दिया हो. मगर ऐसा करके उन्होंने खुद को मुसीबत में डाल लिया है. अब तो यही उनके हक में होगा कि वे जितना हो सके, चुप रहें. यह भी हो सकता है कि इससे अधिक रहस्यों पर से परदा उठने पर होने वाली उथल-पुथल की जिम्मेदारी उन्हीं पर जाएगी. दोनों हालत में इस बात की संभावना है कि इस सब की कीमत ज्ञानी जी को ही चुकानी पड़े.

—प्रभु चावला

विपक्षी नेताओं के साथ जैल सिंह

टी.एस. अशोक

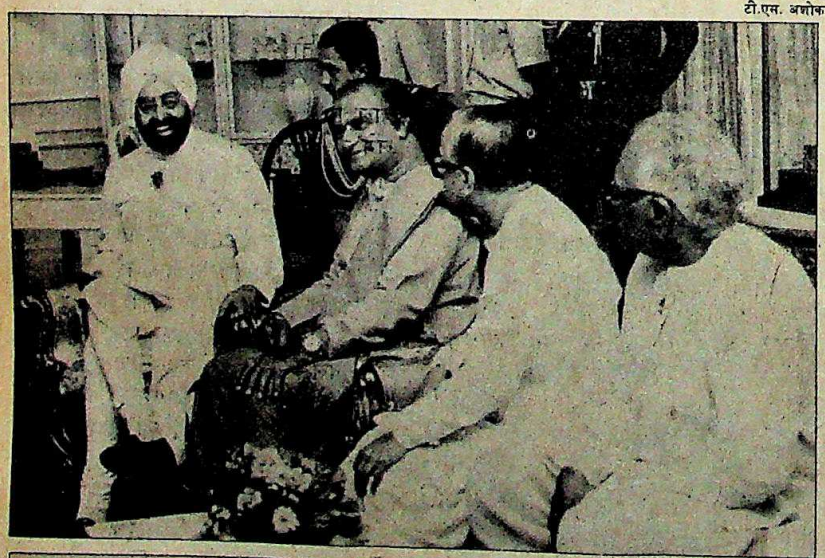

जैल सिंह को राजनीति से बहुत प्यार है. राष्ट्रपति रहते हुए भी उन्हें पत्रकारों और राजनीतिकों के साथ गपबाजी में जितना मजा आता था उतना किसी और चीज में नहीं

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विपक्ष

नया उत्साह

एकता की कोशिशें जोरों पर

गर्मियां आने में हालांकि ज्यादा देर नहीं है पर देश का राजनैतिक माहौल कई कारणों से गरमाने लगा है. इंका में विभिन्न स्तरों पर नेतृत्व परिवर्तन के कारण उत्साह है तो विपक्ष भी खम ठोंकने में लगा हुआ है. विपक्ष सिर्फ ताल ही नहीं ठोंक रहा, बल्कि कुछ कर भी रहा है. 7 मार्च को जनता पार्टी और लोकदल (अ) का औपचारिक विलय हो गया. 9 मार्च को लोकदल (ब) और भाजपा ने दिल्ली में एक विशाल रैली की जिसमें राजीव सरकार को हटाने की मांग की गई. उसी दिन उनका 'दिल्ली बंद' भी कामयाब रहा. वाम मोर्चा और राष्ट्रीय मोर्चा मिलकर 15 मार्च को भारत बंद करने का फैसला भी कर चुके हैं.

चंद्रशेखर (बाएं) और नए कार्यवाहक अध्यक्ष अजीत सिंह; तथा (दाएं) हेगड़े

लेकिन सबसे महत्वपूर्ण घटना लोकदल (अ) के जनता पार्टी में विलय की रही है. हालांकि इससे जनता पार्टी में विभाजन का खतरा पैदा हो गया है. विपक्षी एकता की उम्मीदें पहले से दिखने लगी थीं. जनता पार्टी, लोकदल (अ), कांग्रेस (स) और वी.पी. सिंह के जनमोर्चा के गठजोड़ से राष्ट्रीय मोर्चा अस्तित्व में आ गया था.

जपा-लोकदल (अ) विलय का मामला शुरू से ही संदेहों के घेरे में था. पिछली जुलाई में लोकदल (अ) के अध्यक्ष अजीत सिंह ने जनता पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर को चिट्ठी लिखकर विलय का सुझाव दिया था. इसके बाद दोनों दलों में एकता के तौर-तरीके तय करने के लिए जनता पार्टी ने अपने पांच नेताओं—जॉर्ज फर्नांडीस, बीजू पटनायक, मधु दंडवते, रामकृष्ण हेगड़े और इंदूभाई पटेल की एक टीम बना दी थी. इस टीम को लोकदल (अ) से विचार-विमर्श करने के अलावा लोकदल (ब) के साथ भी ऐसे ही समझौते का प्रस्ताव रखना था.

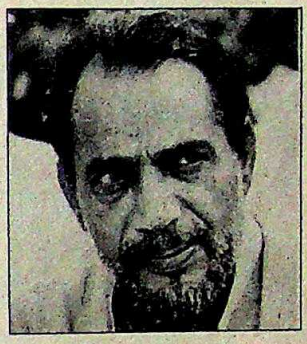

कुछ नेताओं का ख्याल था कि चंद्रशेखर के स्थान पर रामकृष्ण हेगड़े को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए

जनता पार्टी में लोकदल के दोनों धड़ों के विलय का मकसद हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान जैसे हिंदीभाषी इलाकों में अपनी (जपा की) स्थिति मजबूत करना ही है. इन क्षेत्रों से लोकसभा के 174 सदस्य चुने जाते हैं.

लेकिन विलय की प्रक्रिया में लोकदल (ब) को शामिल करने के प्रस्ताव पर मामला ठंडा पड़ने लगा. लोकदल के विभाजन से क्षुब्ध देवीलाल अजीत सिंह के साथ किसी तरह का तालमेल नहीं रखना चाहते थे. अंततः इस वर्ष जनवरी में बंगलूर में हुई बैठक में चंद्रशेखर को इस विलय को सरंजाम देने की जिम्मेदारी सौंपी गई.

चंद्रशेखर अपने दल के वरिष्ठ नेताओं को बमुश्किल यह यकीन दिलाने में कामयाब हो पाए कि अजीत सिंह को पार्टी का अध्यक्ष बनाना सबके लिए फायदेमंद रहेगा. अजीत सिंह को अध्यक्ष बनाने के दो बड़े मकसद थे. एक तो यह कि चंद्रशेखर को इस बात का एहसास था कि 1977 से पार्टी अध्यक्ष बने रहने के कारण उनकी आलोचना की जा रही है. दूसरे अजीत सिंह को अध्यक्ष बनाने से उनकी पार्टी वालों को यह कहने का मौका नहीं मिल पाता कि विलय के बाद जपा का चुनाव चिन्ह, झंडा और नाम स्वीकार करके अजीत सिंह ने लोकदल (अ) को जपा के हाथों बेच डाला है.

लेकिन पटनायक और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेश प्रताप चौधरी की अगुआई में जनता पार्टी के ही एक तबके ने अजीत सिंह को अध्यक्ष बनाए जाने के कदम को चुनौती दी. बदले में उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े का नाम सुझाया.

अजीत सिंह का इस पर कहना था कि "मैं विपक्ष की एकता में बाधक नहीं बनूंगा." जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का भी कहना था कि अजीत के साथ हुए अलिखित समझौते में यह बात भी शामिल है कि यदि उनके कारण जनता पार्टी में लोकदल (ब) के विलय में अड़चन आती है तो वे अध्यक्ष पद से हट जाएंगे.

विपक्षी एकता के रास्ते में एक और रुकावट है—लोकदल (ब) और भाजपा के गठबंधन की. हरियाणा में दोनों दलों की साझी सरकार है. वाम मोर्चे को लोकदल (ब) से तो कोई परहेज नहीं है पर भाजपा से वे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते. फिलहाल विपक्ष के नेता यह गुत्थी सुलझाने में लगे हुए हैं. दिल्ली की रैली में वी.पी. सिंह शामिल हुए और अब सब के साथ 'भारत बंद' सफल बनाने में जुटे हैं.

विपक्ष के बड़े नेताओं का अनुमान है कि ये लक्षण अगले आम चुनाव से पहले विपक्ष के एक हो जाने के ही हैं. इस दिशा में पहला कदम होगा—एक-सी विचारधारा रखने वाले दलों—दोनों लोकदल, जनता पार्टी, राष्ट्रीय संजय मंच, कांग्रेस (स) और जनमोर्चा का विलय. दूसरा कदम होगा क्षेत्रीय दलों—तेलुगु देशम, द्रमुक और असम गण परिषद के साथ गठबंधन करना.

लेकिन पहले की तरह शायद इस बार भी एकता के ये प्रयास इन दलों की आपसी कलह के कारण सफल न हो पाएं. लोकदल (अ) और जनता पार्टी के विलय पर उठा बवाल इसी का संकेत हो सकता है.

—पंकज पचौरी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दिल्ली

बच्चों पर बवाल

गोरखधंधा और उलझा

राजबाला का बच्चा गुम होने का मामला पिछले पखवाड़े और रहस्यमय बन गया. फरवरी भर में चार बच्चों की, जिनमें एक मृत भी था, तफ्तीश करने के बाद दिल्ली पुलिस ने आखिरकार एक बच्चे को ढूंढ़ ही लिया. राजबाला ने उसे जनवरी में पैदा होते ही गुम हुआ अपना बच्चा मानकर अपना लिया. और जैसे ही लगा कि यह तमाशा खत्म हो गया है, यह खबर आ गई कि इस बच्चे का खून उसके मां-बाप से नहीं मिल रहा है.

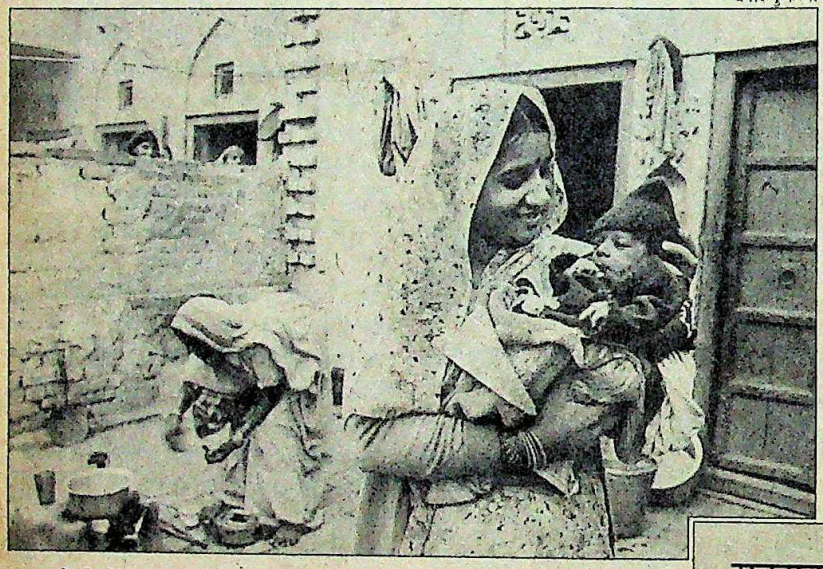

प्रमोद पुष्करणा

गोदी में बालक लिए राजबाला

एक ओर राजबाला इस बच्चे को रखे हुए है तो दूसरी ओर अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं. गुम हुए बच्चे के इस प्रकरण से एक बात जरूर उजागर हुई कि इतने बड़े सरकारी अस्पताल में भी बच्चे लापरवाही से रखे जाते, गुम होते और बेचे जाते हैं.

दिल्ली के खिड़की गांव की राजबाला ने महेंद्र सिंह चौहान से अपनी शादी के 11 महीने बाद 13 जनवरी को 3.12 मिनट पर एक बेटे को जन्म दिया. समय से पहले जन्मे इस कमजोर बच्चे को अस्पताल की नर्सरी में रखा गया.

राजबाला का कहना है कि 18 जनवरी को उसे पीलिया और गर्दनतोड़ बुखार होने के पहले उसने तीन बार इस बच्चे को दूध पिलाया. उसने तीनों बार बच्चे के कपड़े बदले और देखा कि वह बेटा है. फिर दस दिनों तक बच्चे को अलग रखा गया और वह रोज अपना दूध निकाल कर भेज देती थी. जब 28 जनवरी को उसे फिर बच्चे को दूध पिलाने को दिया गया तो एकदम अंधेरा था. राजबाला बताती है, "एकाएक बिजली चली गई और जब मैं नर्सरी से बाहर आई तो बिजली आ गई."

इस संदेहास्पद प्रकरण के दो दिन बाद बच्चा राजबाला के वार्ड में लाया गया. पहले उसे सौंपे गए बच्चे से यह बच्चा ज्यादा गोरा और छोटा था. इसकी उंगलियां भी छोटी थीं. राजबाला ने इसके कपड़े उतारे तो पाया कि यह लड़की है. और फिर शुरू हुई उसकी अस्पताल के अधिकारियों से लड़ाई जो यही समझाते रहे कि उसने लड़की को ही जन्म दिया था. उसके रिश्तेदारों ने पुलिस को खबर दी और यह पूरा मामला अखबारों में भी आ गया.

राजबाला के बच्चे के गुम होने के इस ताजा प्रकरण ने बच्चों की चोरी की चली आ रही धंधेबाजी की ओर ध्यान आकर्षित किया है

राजबाला महीने भर तक अस्पताल में संकल्प किए बैठी रही और अस्पताल के अधिकारी, पुलिस और अखबार वालों तथा दूसरे लोगों की भीड़ जुटी रही. जब अस्पताल के पैथॉलाजी विभाग के प्रमुख डॉ. वी.एच. तालिब ने जांच करके बताया कि उससे बेटा ही जन्मा था. तभी जाकर पुलिस ने इस बच्चे की तलाश शुरू की.

तालिब की रिपोर्ट में कहा गया था कि चूंकि इस बच्चे को उसी समय जन्मी बच्ची के साथ एक ही ट्रे में नर्सरी में ले जाया गया, इसलिए हो सकता है कि अदला-बदली हो गई हो. दूसरा बच्चा मर गया था. जांच से पता चला कि वह लड़की थी.

तब पुलिस ने उन सभी 40 महिलाओं से पूछताछ की जिन्होंने उस समय के आसपास बच्चे को जन्म दिया था. राधा नामक एक ऐसी महिला का पता चला जिसने अपना पता गलत लिखाया था. पुलिस को लगा कि वही बच्चा बदलकर ले गई है. पर राधा के पास उसकी बेटी ही थी. एक पुलिस दल राजस्थान में अलवर भी गया जहां की हसीना को उसी समय बच्ची पैदा हुई थी. पर हसीना के पास भी उसकी बेटी ही थी.

लेकिन 25 फरवरी को जब राजबाला रोते हुए अस्पताल छोड़ने पर राजी हो गई उसके कुछ देर बाद ही खुर्जा से आए एक व्यक्ति ने बताया कि वहां के स्टेशन के एक दुकानदार को एक बच्चा पटरी के पास पड़ा मिला है. पुलिस उस बच्चे को दिल्ली ले आई और राजबाला को दिखाया. उसने बड़े भरोसे से कहा, "यह तो जरा भी नहीं बदला. अभी भी बहुत कमजोर है. इसके नाकनक्श वही हैं." खून की जांच से जो भी नतीजा निकले वह इसे रखने का पक्का निश्चय कर चुकी थी.

राजबाला को उसका असली बच्चा मिला या नहीं, पर इस प्रकरण ने अस्पताल की कुव्यवस्था को उजागर जरूर कर दिया. सफदरजंग अस्पताल के जिस वार्ड में औरतों को बच्चा होता है वहां एक झीना परदा भर है और हर समय करीब दर्जन भर औरतों की प्रसूति हो रही होती है. इस पर एक डॉक्टर की मजाकिया टिप्पणी थी, "यह तो किसी रेलवे प्लेटफार्म की तरह है." यहां बच्चों के मामले में गड़बड़ की पर्याप्त संभावनाएं हरदम रहती ही हैं.

बच्चा होने की पीड़ा से तड़पती मां को बहुत होश रहता नहीं. ऐसे में बच्चों की अदला-बदली और चोरी होने की बहुत संभावना रहती है. और ऐसी गड़बड़ करने वाला गिरोह सक्रिय है, यह तो स्पष्ट ही है. सफदरजंग अस्पताल में ही एक वर्ष में कम से कम दो ऐसे मामले सामने आए हैं.

चूंकि राजबाला पढ़ी (आठवीं तक) हुई थी और उसके ससुर एक पार्षद को जानते थे इसलिए इस परिवार को अपनी आवाज ऊपर तक पहुंचाने में कामयाबी मिल गई. राजबाला कहती है कि बच्ची देने से पहले

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जो प्रमुख टू-व्हीलर निर्माताओं की पसंद है
आप भी वही टायर्स चुनिए

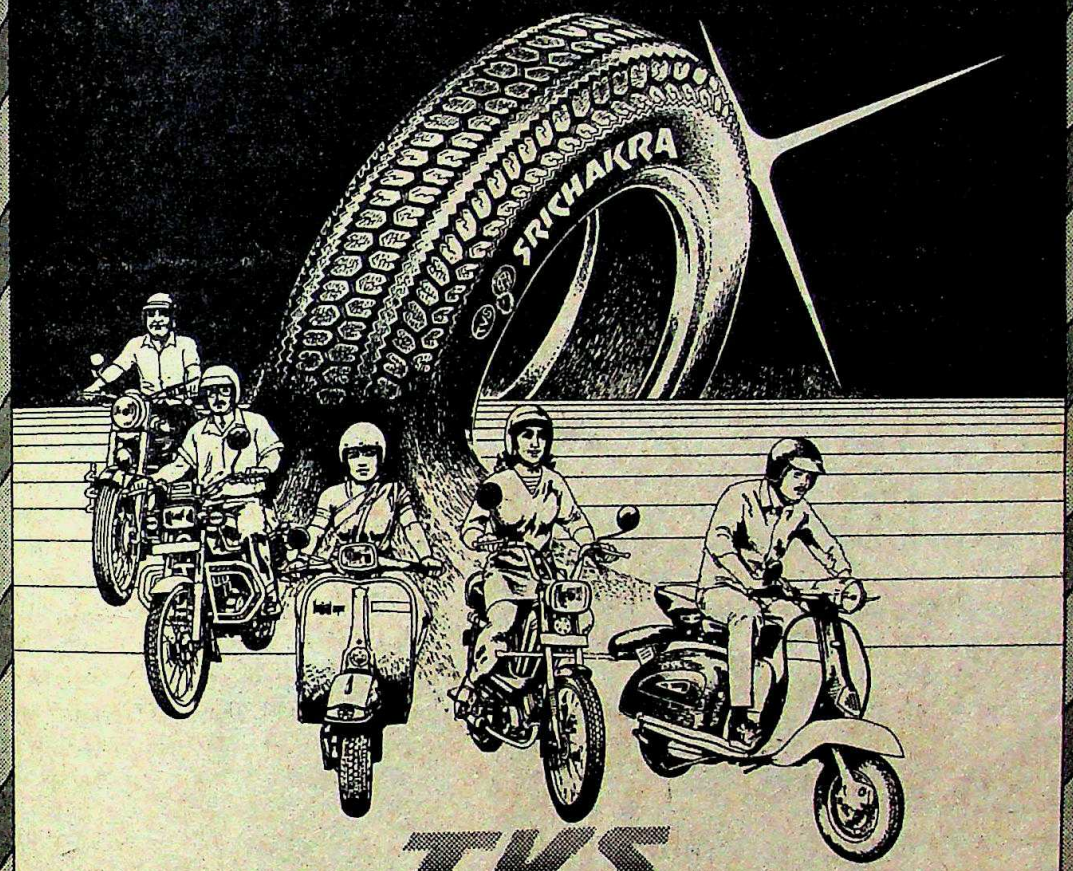

TVS
SRICHAKRA

मौलिक साधन पसंद करने वाले भारत के सभी प्रमुख टू-व्हीलरों के लिए. ज़्यादा सुरक्षा और भरोसेमंद पकड़ के लिए मज़बूत बनाए गए.

सचमुच अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टायर. श्रीचक्रा बनाने वाले हैं टी वी एस - 'ऑटो एन्सीलियरीज़' में जाना-माना एक विश्वसनीय नाम.
भारत के ऊबड़-खाबड़ रास्तों के लिए ख़ासतौर से बनाए गए. श्रीचक्रा टायर ऐसी अनोखी खूबियों से बने हैं जो आपको दें उत्तम कार्यकुशलता और ज़्यादा माइलेज. साथ ही रीट्रेडिंग के लिए इसमें कमाल की गुंजाइश है.
इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सभी प्रमुख टू-व्हीलर निर्माता टी वी एस श्रीचक्रा ही पसंद करते हैं.

LTL/SS/47/HN

TVS SRICHAKRA TYRES

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नर्सों ने पूछा था कि उसके पति, पिता और ससुर क्या करते हैं. उसकी सास गेंदो देवी कहती हैं, "वे सोचते हैं हम लोग गांव वाले हैं, क्या कर लेंगे?" यह सही भी है.

बड़े अस्पतालों के इस उपेक्षापूर्ण रवैये के कारण धंधेबाजों की बन आती है जो नवजात शिशुओं, वह भी लड़कों को चुरा-कर निस्संतान दंपतियों को बेच देते हैं. अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से सहायता प्राप्त अनाथालय, 'उदयन' की सलाहकार लक्ष्मी कृष्णन बताती हैं कि जब से गर्भपात को कानूनी मान्यता मिल गई है, तब से बच्चों की मांग बहुत बढ़ गई है. वे कहती हैं, "किसी अनाथालय में नाम दर्ज कराने के बाद चार-चार वर्ष की प्रतीक्षा के बाद बच्चे मिल पाते हैं." ऐसे में चोरी के बच्चों की बिक्री ज्यादा मुनाफे का धंधा हो गई है.

सबसे ज्यादा कमाई विदेशों में होती है क्योंकि विदेशी जोड़े भारतीय शिशुओं को गोद लेना चाहते हैं. वे रंग में काले शिशुओं और बच्चियों को भी उसी भाव से लेते हैं. कृष्णन बताती हैं कि भारतीय और खासकर संयुक्त परिवार वाले बच्चियों को गोद लेना नहीं चाहते. पश्चिम के लोग, शिशुओं को लाने वालों को विदेश आने-जाने का खर्च भी देते हैं. कृष्णन बताती हैं कि एक बच्चे को गोद लेने पर वे आसानी से तीन-चार हजार डॉलर (39 से 52 हजार रुपए) खर्च कर डालते हैं.

सातवें दशक में जब विदेशों में बच्चे बेचे जाने पर हंगामा मचा था तो सरकार ने विदेशी जोड़ों को बच्चे गोद देने का जिम्मा कुछ लाइसेंस प्राप्त संगठनों पर सौंप दिया था. ऐसी कुछ संस्थाओं के कर्मचारी बताते हैं कि अब भी चोरी-छिपे विदेशी जोड़ों को बच्चे बेचने का काम चल ही रहा है.

ऐसा कोई कानून नहीं है जो इन धंधे-बाजों को गोद में बच्चा ले जाकर विदेशों में बेच देने से रोक सके. विदेशियों को भी कागजी झमेले निपटाने के बजाय यह तरीका आसान लगता है. लेकिन कई बार ये लोग पैसा लेकर भी बच्चा नहीं देते. पिछले साल बेल्जियम दूतावास को ऐसी शिकायतें मिलीं कि पैसा देने पर भी वहां के कई जोड़ों को बच्चे नहीं मिले. दूतावास के एक अधिकारी एम. वांत्रोयन कहते हैं कि मध्य '87 के बाद ऐसी शिकायतें बढ़ी हैं.

लेकिन ऐसी शिकायतों से यह धंधा बंद नहीं होता. पिछले पखवाड़े भी जिस बच्ची को राजबाला का बताकर उसे सौंपने की कोशिश की गई, वह कहां से आई अभी इसका पता नहीं चल पाया है.

—डेविड देवदास और बी. रवि

गुरुदास कामत

इल्म पर इल्जाम

युवक इंका अध्यक्ष मुश्किल में

युवक कांग्रेस अध्यक्ष गुरुदास कामत के लिए पिछले कुछ सप्ताह कई सनसनी-खेज घटनाएं लिए आए. पहले तो वे भुनभुनाते रहे. इसी बीच कुछ अखबारों ने छापा कि उन्होंने इंका महासचिव ऑस्कर फर्नांडीस से अन-बन के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने इसका तुरतफुरत खंडन कर दिया. लेकिन असल मुश्किल तो उन्हें तब पेश आई जब उनकी शैक्षणिक योग्यता पर ही सवाल उठा दिया गया.

गुरुदास कामत

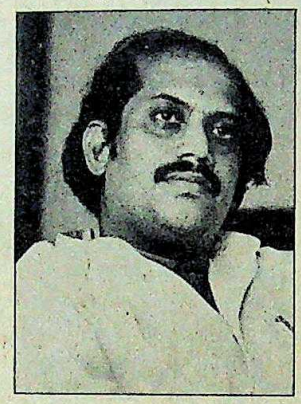

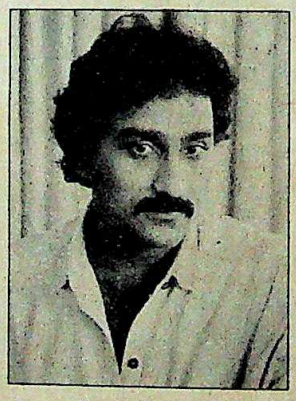

भूपिंदर सिंह गुप्ता

33 वर्ष की उम्र में उनके पास कई डिग्रियां हो गई हैं. उन्हें पोद्दार कॉलेज से स्नातक परीक्षा में उम्दा अंक पाने के लिए पदक और अमेरिका के मिसौरी की 'द इंटरनेशनल यूनि-वर्सिटी' (टीआइयू) से एमबीए की डिग्री प्राप्त करने का रुतबा हासिल है.

लेकिन उनकी आखिरी डिग्री पर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ की बंबई शाखा के पूर्व अध्यक्ष भूपिंदर सिंह गुप्ता ने सवाल उठा दिया है. गुप्ता का आरोप है कि कामत की एमबीए की डिग्री फर्जी है और उनके दोस्त डॉ. जी. एम. कोठारी तथा उनके बेटे अरुण और अरविंद ऐसी संस्थाएं चलाते हैं जो 'फर्जी' अमेरिकी विश्वविद्यालयों के नाम से ऐसी डिग्रियां बांटा करती हैं.

हालांकि कामत ने इन इल्जामों पर तो ध्यान नहीं दिया. लेकिन 'सिद्धार्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्री ऐंड एडमिनिस्ट्रेशन (एसआइ-आइए) (जिसके अवैतनिक निदेशक कोठारी हैं), और अरविंद द्वारा चलाए जाने वाले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (एनआइएम) और युवा इंका के कार्यकर्ता अरुण ने इसका खंडन किया और गुप्ता के खिलाफ मानहानि का दावा ठोंक दिया.

गुप्ता ने इल्जाम लगाया कि कामत कभी भी अमेरिका नहीं गए लेकिन अखबारों में दिए विज्ञापनों में उन्होंने वहां से एमबीए की डिग्री लेने का दावा किया है. कामत सफाई देते हैं, "मैंने कभी अमेरिका जाने का दावा नहीं किया. मैंने डाक से एक कोर्स पूरा किया है." हालांकि डिग्री तो अपने आप में जायज कही जा सकती है पर टीआइयू की साख संदेह के घेरे में है.

एनआइएम का दावा है कि दुनिया भर में फैली टीआइयू एक कर-मुक्त और गैरव्यावसायिक संस्था है. लेकिन भारत में अमेरिकी शैक्षिक संस्था (यूएस एजुकेशन फाउंडेशन) के एक अधिकारी का कहना है, "टीआइयू को किसी अधिमान्य संस्था से मान्यता नहीं प्राप्त है." अमेरिका में टीआइयू के निदेशक जॉन जॉन्स्टन ने टेलीफोन पर बात करने से इनकार कर दिया. उनका कहना था कि वे लिखित सवालों के ही जवाब देंगे.

पर कामत कहते हैं, "अगर ये संस्थाएं फर्जी साबित होती हैं तो इन पर रोक लगा देनी चाहिए." असल में उनके विरोधियों ने एकाधिकार और प्रति-बंधात्मक व्यापार आयोग में टीआइयू की जांच के लिए याचिका दायर की है. पर आखिरी सूचना मिलने तक टीआइयू का कामकाज बदस्तूर चल रहा है. अल-बत्ता इसने एनआइएम से अपने रिश्ते जरूर तोड़ लिए हैं. यह अब 'द नेशनल फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज' के नए नाम से अपना काम चला रही है.

कामत ही ऐसे इंकाई सांसद नहीं हैं जिनकी शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाया गया हो. पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी को अपनी अमेरिकी पीएचडी के मात्र कागजी दस्तावेज होने की जानकारी मिले अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं. लेकिन कामत के मामले ने खास फीस के एवज में सब कुछ दिलाने का वायदा करने वाली इस तरह की संस्थाओं पर अंकुश लगाने की जरूरत पर रोशनी तो डाली ही है.

—सलिल त्रिपाठी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पश्चिम बंगाल

आपस में लड़े और जीते

पंचायत चुनावों को लेकर वाम मोर्चे के दलों में घमासान

वामपंथी मोर्चे ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उसका 'लाल किला' अजेय है. पिछले पखवाड़े पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनावों में माकपा की अगुआई वाले मोर्चे ने स्थानीय प्रशासन के तीनों ही स्तरों पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली. ग्राम पंचायतों की लगभग 70 प्रतिशत, पंचायत समितियों की 77 प्रतिशत और जिला परिषदों की सभी सीटों पर इसने जीत हासिल की.

कल्याण चक्रवर्ती

पंचायत चुनावों को लेकर माकपा और उसके सहयोगी दलों में हुए घमासान से साफ जाहिर हो गया वाम मोर्चा अब पहले की तरह मजबूत नहीं रहा

नौ दलों के गठजोड़ वाले इस मोर्चे के सबसे बड़े दल माकपा के प्रमुख सहयोगी दलों—फारवर्ड ब्लॉक और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) ने न केवल माकपा उम्मीदवारों के मुकाबले अपने उम्मीदवार खड़े किए बल्कि मार्क्सवादियों के खिलाफ उन्होंने जहर भी खूब उगला.

नतीजतन 16 जिलों की 62,300 सीटों के लिए मोर्चे के 73,000 उम्मीदवार मैदान में उतर आए (गोरखा आंदोलन के कारण दार्जिलिंग में चुनाव नहीं कराए गए). मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने अपने पहले चुनावी भाषण में फारवर्ड ब्लॉक और आरएसपी की सीटों की मांग को 'अनुचित' ठहराकर जैसे बर्र का छत्ता ही छेड़ दिया. उन्होंने मतदाताओं से आग्रह किया कि वे वामपंथी मोर्चे की एकता को नुकसान पहुंचाने वाले दलों को वोट न दें.

माकपा के सहयोगी दलों ने भी नाराजगी छिपाने की कोई कोशिश नहीं की. फारवर्ड ब्लॉक के कृषिमंत्री कमल गुहा ने कूचबिहार जिले में सब जगह पोस्टर चिपकवा दिए थे, जिन पर लिखा था—'राजीव हटाओ, देश बचाओ' और 'माकपा हटाओ, ग्राम बचाओ'. आरएसपी के नेता तथा सिंचाई और नहरमंत्री देबव्रत बंद्योपाध्याय ने मार्क्सवादियों की तुलना 'सामाजिक फासिस्टवादियों से कर डाली जो स्टालिन की तरह अपने सहयोगी दलों को मिटाने' की कोशिश कर रहे हैं.

फारवर्ड ब्लॉक और आरएसपी ने इंका की तर्ज पर ही माकपा पर चुनाव में गडबड़ी करने और आतंक फैलाने के आरोप मढ़े. इंका और दूसरी वामपंथी पार्टियों का चुनाव प्रचार माकपा के भ्रष्टाचार और चुनावी जीत हासिल करने के लिए उसके द्वारा उठाए गए अनुचित कदमों पर ही केंद्रित रहा.

मार्क्सवादी भी खामोश नहीं रहे. पार्टी के मुखपत्र 'गणशक्ति' ने मतदान से दस दिन पहले इस बात के पुख्ता सबूत होने का दावा किया कि फारवर्ड ब्लॉक और आरएसपी ने इंका से गलबहियां डाल ली हैं. इस 'रहस्योद्घाटन' के बाद मोर्चे के बड़े नेताओं ने मेल-मिलाप की कोशिशें कीं पर वे कामयाब नहीं हुए.

लेकिन मोर्चे की इस फूट से इंका कोई फायदा नहीं उठा पाई. उसकी झोली में पंचायतों की सिर्फ 13,000 सीटें ही आईं जबकि 1983 के चुनाव में उसने 14,000 सीटें हासिल की थीं. पश्चिमी दीनाजपुर और हावड़ा जिलों में इंका ने अपनी स्थिति में कुछ सुधार किया लेकिन बदले में मालदा जिला परिषद उसके हाथ से निकल गई.

हालांकि पार्टी के नेता चुनावी गड़बड़ियों को अपनी हार का कारण बताते हैं लेकिन एक महत्वपूर्ण वजह यह भी थी कि पार्टी 10,152 सीटों पर अपने उम्मीदवार ही खड़े नहीं कर पाई. प्रदेश इंका अध्यक्ष प्रियरंजन दासमुंशी गुस्से से कहते हैं, "हम ज्यादा उम्मीदवार खड़े नहीं कर पाए इसी से पता चल जाता है कि पश्चिमी बंगाल में माकपा के आतंक से लोकतंत्र कैसे मजाक बनकर रह गया है."

बसु अब इस बात पर जोर दे रहे हैं कि फारवर्ड ब्लॉक और आरएसपी के नेता चुनाव अभियान के दौरान दिए गए बयानों का लिखित स्पष्टीकरण दें. फारवर्ड ब्लॉक के युवा नेताओं ने ऐसा करने से इनकार कर दिया. इसलिए दल के राज्य सचिव अशोक घोष ने कहा है, "हमारे नेताओं ने मुख्यमंत्री या सरकार की आलोचना नहीं की."

यदि वामपंथी मोर्चा अपने मतभेद नहीं मिटा पाता तो फारवर्ड ब्लॉक और आरएसपी जैसे मोर्चे के गैर-कम्युनिस्ट दलों से माकपा और भाकपा की दूरी बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. यदि मोर्चे में असंतोष बढ़ता ही गया तो उसकी हालत भी इंका की राज्य इकाई जैसी ही हो जाएगी.

—कमलजीत रतन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कांग्रेस (इ)

बदलते दांवपेच

दो पार्टी अध्यक्ष बदले गए

पिछले पखवाड़े इंका नेतृत्व ने जो किया उससे अलग ही तरह का संकेत मिला. पार्टी नेताओं ने अचानक दांवपेच बदल लिए. ओडीसा के मुख्यमंत्री जानकीबल्लभ पटनायक और बिहार के मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद खुश-किस्मत निकले कि उन्हें ऐसे प्रदेश इंका अध्यक्ष मिले जिनसे उनकी अच्छी पट सकेगी. वरना अभी तक तो पार्टी के आला नेताओं को प्रदेशों में ऐसे अध्यक्ष नियुक्त करने में ही मजा आता था जिनकी मुख्यमंत्री से खटकती रहे.

जानकी बल्लभ पटनायक

कान्हूचरण लेंका

पटनायक को जब पता चला कि उनके करीबी लेंका को प्रदेश इंका अध्यक्ष बनाया जा रहा है तो उनकी बांछें खिल गईं

इसीलिए जब 38 वर्षीय तारिक अनवर को बिहार इंका अध्यक्ष बनाया गया तो आजाद ने गदगद होकर प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया. उधर पटनायक को भी जब पता चला कि उनके सिरदर्द सांसद नित्यानंद मिश्र को प्रदेश इंका अध्यक्ष पद से हटाकर 48 वर्षीय कान्हूचरण लेंका को उस कुर्सी पर बिठाया जा रहा है तो उनकी भी मानो बांछें खिल गईं.

दोनों राज्यों के राजनैतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि राजीव गांधी अब देर-सबेर पार्टी के नाकारा हो चुके नेताओं को तराशने और सक्रिय कार्य-कर्ताओं को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं. कुछ को तो इस बदलाव में आगामी चुनावों का संकेत भी दिखने देने लगा.

बिहार में पार्टी के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं, "अब इंका आपसी उठापटक करती हुई चुनाव में नहीं उतरेगी." उनका आशय था कि अब असंतुष्टों को चुपचाप पड़े रहना होगा. असंतुष्टों को भी यह बात समझ आ गई लगती है. मसलन ओडीसा में बसंतकुमार बिस्वाल के खेमे में मुर्दनी छा गई है. बिस्वाल कभी पटनायक के दोस्त हुआ करते थे पर अब एक अरसे से उनके दुश्मन हैं. लेंका 1980 से ही बिस्वाल विरोधी अभियान की अगुआई कर रहे हैं.

बिहार के मामले में इंका के कोषाध्यक्ष सीताराम केसरी ने तारिक की नियुक्ति में हर मुमकिन अड़ंगा डालने की कोशिश की. उन्होंने केंद्रीय खनन राज्यमंत्री रामानंद यादव से मिलकर गुटबाजी शुरू की. पर केसरी कामयाब नहीं हो सके क्योंकि एक तो यादव पांसा पलटकर तारिक का समर्थन करने लगे और दूसरे राजीव ने पार्टी कोषाध्यक्ष की बात को तरजीह नहीं दी.

नेतृत्व के कड़े रुख का असर भी हुआ. राज्य युवा इंका के अध्यक्ष और शहरी विकास राज्यमंत्री श्याम-सुंदर सिंह 'धीरज' ने तुरंत ही अपना तारिक विरोधी अभियान बंद कर दिया. वे कहते हैं, "हमारे बीच जो मतभेद थे भी, वे अब खत्म हो गए हैं." यहां तक कि जगन्नाथ मिश्र ने भी तारिक के समर्थन की अपील करते हुए कहा, "तारिक मृतप्राय संगठन में फिर से जान फूंक सकते हैं."

देश के सबसे युवा प्रदेश इंका अध्यक्ष तारिक एक चाक-चौबंद व्यक्ति हैं. उन्होंने अपने राजनैतिक जीवन की शुरुआत पटना से की थी, जहां वे युवा इंका के अध्यक्ष थे. बाद में वे राष्ट्रीय युवा इंका और सेवादल के अध्यक्ष बने. दोनों ही संगठनों में उन्होंने कुछ हद तक जान डाल दी. इस समय उनका सबसे बड़ा काम अल्पसंख्यकों को फिर से पार्टी की धारा में लाना है. यह तबका लगातार पार्टी से दूर होता जा रहा है.

भागवत झा आजाद

तारिक अनवर को बिहार इंका का नया अध्यक्ष बनाने पर आजाद ने राजीव का शुक्रिया अदा किया

तारिक अनवर

पर ओडीसा में लेंका की प्राथमिकताएं अलग ही हैं. उन्हें ऐसे मुख्यमंत्री के साथ काम करना है जिसने पिछले आठ साल में राजनैतिक आधार काफी खो दिया है. उनका काम अब इस वजह से आसान है कि वे पटनायक के करीबी हैं, हालांकि पहले वे एक दूसरे को फूटी आंखों नहीं सुहाते थे.

1980 में लेंका को राजस्व मंत्रालय देकर पटनायक मंत्रिमंडल में दूसरे नंबर पर रखा गया. तब से ही उन्होंने पटनायक के उस समय के विश्वासपात्र बिस्वाल की गतिविधियों का विरोध करना शुरू कर दिया. इससे खफा होकर पटनायक ने 16 महीनों के अंदर ही अपने इस नंबर दो सहयोगी को बरखास्त कर दिया था.

प्रतिकूल हालात के बावजूद लेंका ने बिस्वाल विरोधी, पटनायक विरोधी रवैया कायम रखा. पिछले साल तक यही स्थिति बनी रही. उसी समय बिस्वाल भी पटनायक का साथ छोड़ गए, असंतुष्ट विधायकों की संख्या 80 का आंकड़ा पार कर गई और नित्यानंद मिश्र भी मुख्यमंत्री का विरोध करने लगे. पर लेंका ने असंतुष्टों को मझधार में छोड़ पटनायक की आलोचना का स्वर धीमा कर दिया.

एक इंका नेता के अनुसार, "पार्टी में असंतोष खत्म करने की उनकी कोशिशों को आलाकमान ने भी मान्यता दे ही दी." उन्हें अब सारा जोर किसानों का समर्थन जुटाने में लगाना होगा. विपक्ष इस वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब रहा है.

लेंका और तारिक दोनों को विपक्ष की कमजोरियों का फायदा उठाते और अपनी खामियों को छिपाए रखते हुए अगले चुनाव के सिलसिले में अपनी नजर साफ रखनी होगी. आगामी चुनाव उनके लिए चरदान हैं. इसीलिए इंका ने एक दूसरे को नियंत्रित करते मुख्यमंत्री और प्रदेश पार्टी अध्यक्ष बनाने की अपनी नीति बदल दी है.

—फरजंद अहमद

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उषा आज! उषा अब!

चमकते दमकते मोतियों से
सफ़ेद, स्टैला, पल्सर, प्राइमा.

सुनहरे व भूरे सरताज: कोहिनूर
सुपर डीलक्स, सेनेटर और नया
सजीला तीन-ब्लेड पल्सर.

उषा के विस्तार का जवाब नहीं.
विलासपूर्ण आराम भी, आसान दाम
भी. हर पसंद, हर डिज़ाइन के पंखे.

और कई दूसरे आकर्षक सितारे
भी-तरह-तरह के टेबिल, वॉल,
कैबिन, पैडेस्टल और वेंटिलेटिंग पंखे.
उषा की उत्तम तकनीक से गढ़े,
दुनिया के पारखी लोगों के लिये उषा
पंखे-रूप उत्तम, बिकें अधिकतम.

कोहिनूर सुपर डीलक्स

पल्सर डेकोरेटिव

कोहिनूर सुपर डीलक्स

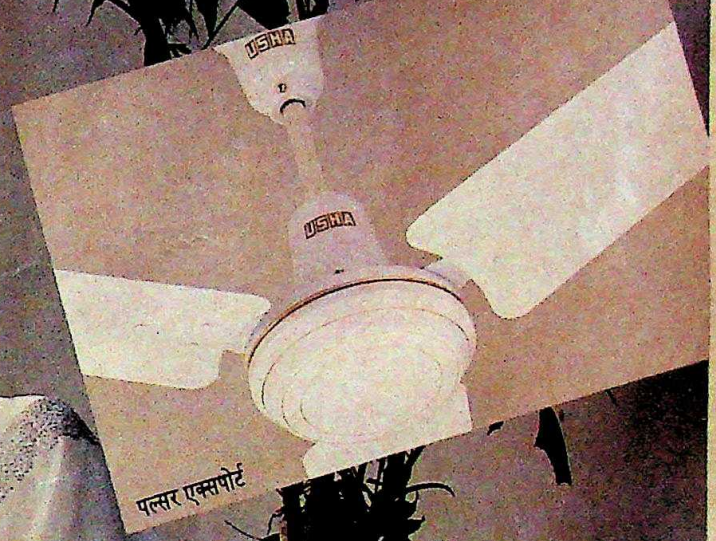

पल्सर एक्सपोर्ट

महलों का मोती

USHA उषा

भारत का सर्वाधिक बिकने वाला पंखा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Fo

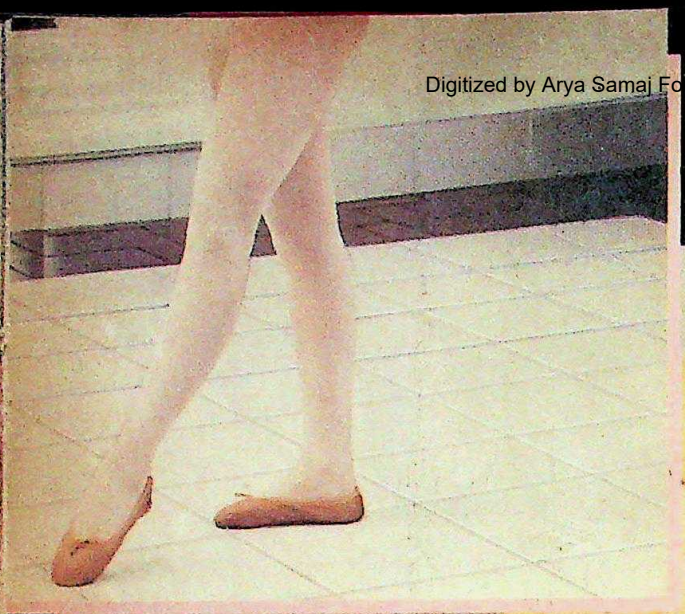

खूबसूरत बात, स्पारटेक फ़्लोर्स में बहुत कुछ पाएंगे आप...

स्पारटेक

५२, चेमियर्स रोड, मद्रास-६०० ०२८

भारत में सबसे ज़्यादा बिकनेवाले सिरामिक फ़्लोर टाइल्स

इन पर फिसलने का डर भी नहीं!

ज़रा गौर से देखिए और जानिए स्पारटेक फ़्लोर्स के गुण...

- खरौंच से पूरी तरह बेअसर
- दाग-धब्बों से बेअसर
- आग और आंच से बेअसर
- देखरेख और सफ़ाई आसान
- मौजूदा फ़र्श पर भी आसानी से लगाये बिठाये जा सकते हैं और ४८ घंटों में ही फ़र्श इस्तेमाल कर सकते हैं
- अनेकों साइज़ों में उपलब्ध 305 x 305 mm, 305 x 203 mm, 203 x 203 mm, 203 x 101.5 mm एक से बढ़कर एक मनभावन रंगों में.

ये सारी खूबियां और खूबसूरती ऐसी कि आप देखते रह जाएं.

स्पारटेक फ्लोर्स दिखने में खूब, इस्तेमाल में खूब, हर पहलू से खूब

...undation Chennai and...

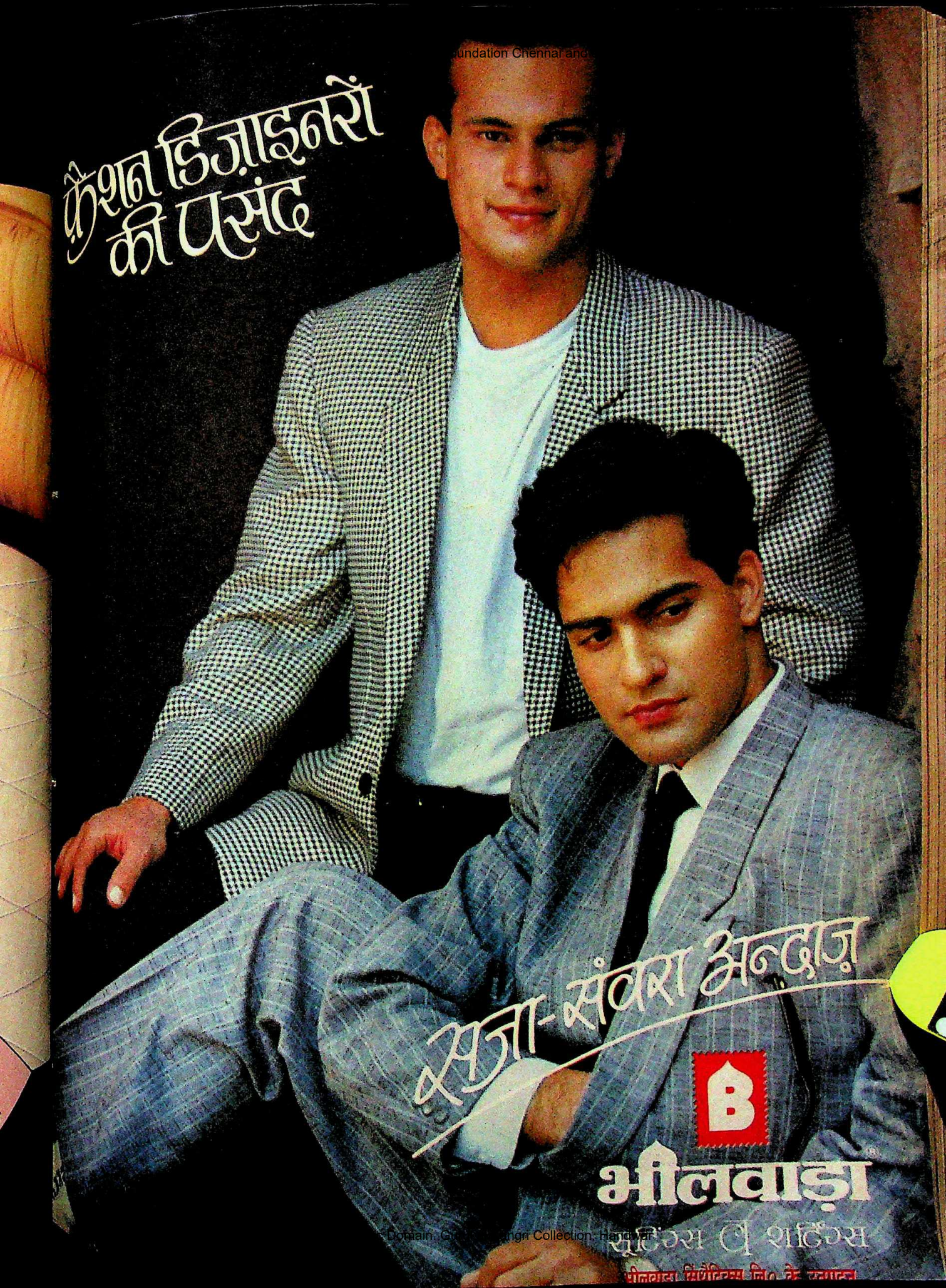

...Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तुरन्त! प्रकृति का प्यार-भरा उपचार दे

वूंड + एड —घाव के लिये

प्राचीन जड़ी बूटियों से बनी इस हर्बल औषधि को स्प्रे कीजिये. घाव को पहले साफ़ करने की भी ज़रूरत नहीं. त्वचा के कटने, छिलने या घाव हो जाने पर निकलने वाला खून तुरन्त बंद हो जायेगा. और घाव ठीक होना शुरू हो

वूंड एड केवल कृमिनाशक ही नहीं. यह शरीर की उपचार क्षमता को बढ़ाकर घाव को जल्दी भरने में सहायक होती है. कोई भी दूसरा इलाज इतनी जल्दी इतना असर नहीं करता.

ब्रूज़ + एड —बंद चोट के लिये

उंगली कहीं दरवाज़े में दब जाये या क्रिकेट की गेंद अचानक बदन को आ लगे तो ख़ासी दर्दनाक बंद चोट पड़ जाती है.

अब पहली बार आप इसका सहज उपचार कर सकेंगे. उस जगह पर ब्रूज़ एड स्प्रे कीजिये. इसमें मिली जड़ी-बूटियां फ़ौरन काम करने लगती हैं. और जानलेवा दर्द बंद करके उस जगह को सूजने व नीला पड़ने से रोकती हैं.

बर्न + एड —जलन के लिये

बर्न एड में ऐसी औषधियां हैं जो पानी से भी कई गुना अधिक ठंडक पहुंचाती है.

इसकी जड़ी-बूटियों से न केवल जली त्वचा को ठंडक पहुंचती है, बल्कि त्वचा के अंदर तक जलन को राहत मिलती है जिससे फ़ायदा देर तक बना रहता है.

और जली त्वचा भी बहुत जल्द अच्छी हो जाती है. बिना एक छाला तक पड़े अगर जलने के बाद तुरन्त बर्न एड लगा दें.

घर में या सफ़र पर, आप जहां कहीं भी हों, राहत के इन तीन उपचारों वाला क्विक-एड-किट अपने पास रखें. ताकि इस बात का इत्मीनान रहे कि कहीं कोई हादसा हो भी जाये तो उससे निबटने के लिये आप तैयार हैं.

क्विक एड किट RKB HERBALS **प्रकृति का प्यार-भरा उपचार**

CC-0. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बिहार पुलिस

तगड़ा झटका

महत्वपूर्ण पदों पर फेरबदल

बिहार के मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद कें तौर-तरीकों को समझने और उनके अनुरूप ढलने में राज्य के राजनैतिक और प्रशासनिक ढांचे को अभी कुछ वक्त लगेगा. पिछले पखवाड़े उन्होंने महत्वपूर्ण पदों पर जो फेरबदल किए उनसे कई लोग अचंभे में हैं.

सबसे चकित कर देने वाला उनका फैसला रहा मध्य प्रदेश काडर के आईपीएस अधिकारी जमील एम. कुरेशी को बिहार का पुलिस महानिदेशक बनाना. इंडो-तिब्बतन बॉर्डर पुलिस (आईटीबीपी) के महानिदेशक कुरेशी को केंद्रीय गृहमंत्री बूटा सिंह की मंजूरी पर बिहार पुलिस महानिदेशक बनाया गया है. कुरेशी एक कड़े अधिकारी के रूप में विख्यात हैं. उन्होंने मध्य प्रदेश में डकैत विरोधी अभियान का नेतृत्व तो किया ही है, जम्मू व कश्मीर सरकार के सुरक्षा सलाहकार भी वे रह चुके हैं.

कुरेशी की नियुक्ति बिहार पुलिस महकमे में भारी उलटफेर का संकेत बनी. उनके पूर्ववर्ती पुलिस महानिदेशक एस.एन. राय को अभी आठ महीने पहले दलेलचक बघौरा हत्याकांड के बाद इस पद पर नियुक्त किया गया था. अब उन्हें होमगार्ड और अग्निशमन सेवा की कमान थमा दी गई है. आरक्षी महानिरीक्षक स्तर के दो पुलिस अधिकारी ललित विजय सिंह और अरुण चौधरी भी चूंकि कुरेशी की तरह 1956 बैच के आईपीएस हैं, सो उन्हें भी पदोन्नति देकर महानिदेशक पद का दर्जा दे दिया गया है. सिंह को बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम का अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक बना दिया गया है. पहली बार किसी पुलिस अधिकारी को इस पद पर नियुक्ति की गई है. और चौधरी को पुलिस आवास निर्माण निगम का अध्यक्ष बनाया गया है.

आजाद ने पिछले पखवाड़े यह संकेत भी दे दिया कि वे लापरवाह पुलिस वालों के प्रति सख्ती बरतने से कतई नहीं हिचकेंगे. पड़रिया में सामूहिक बलात्कार के आरोप में उन्होंने न केवल 14 पुलिस सिपाहियों को निलंबित करवा दिया बल्कि उनमें से 11 पर मुकदमा चलाने के भी आदेश दिए. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था.

किसी 'बाहरी' व्यक्ति को पुलिस प्रमुख बनाए जाने से असंतोष फैलना स्वाभाविक ही था और मुख्यमंत्री ने खुद भी इसे अनुभव किया है. लेकिन वे इस विशाल संगठन में व्याप्त भ्रष्टाचार और निकम्मेपन को दूर करने को कृतसंकल्प दिखते हैं. इधर कुछ वर्षों से बिहार पुलिस जातीय आधार पर बंट गई है. इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देने में बड़े पुलिस अधिकारी भी शरीक रहे हैं और राजनीतिक भी. पुलिस के कामकाज में

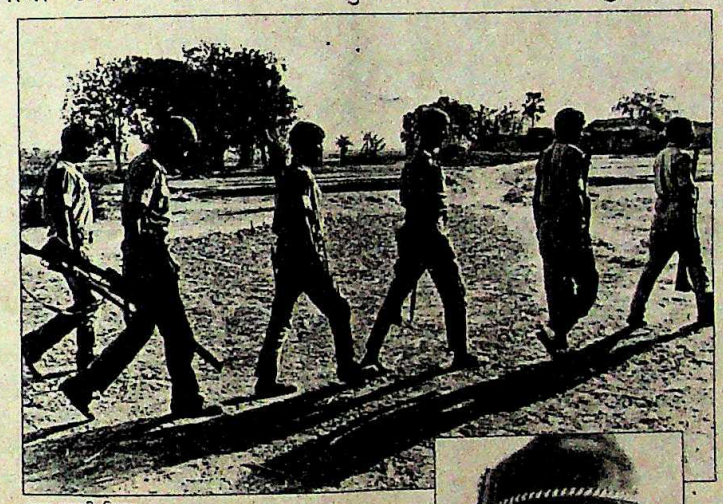

कृष्ण मुरारी किशन

बिहार पुलिस में जान फूंकेंगे कुरेशी (इनसैट)

राजनैतिक दखलंदाजी तो आम बात हो गई है.

इस उलटफेर से, समय से पहले दी गई पदोन्नतियों से बड़े अधिकारियों की संख्या बढ़ी है. कुरेशी के आने से दो की पदोन्नति के बाद महानिदेशक स्तर के सात अधिकारी हो गए हैं. और दूसरी ओर हाल यह है कि राज्य के 1200 थानों में से 413 में न तो टेलीफोन है और न ही वायरलेस.

बिहार पुलिस का हौसला कितना गिर चुका है यह बिहार पुलिस एसोसिएशन (बीपीए) के महासचिव एन.पी. दुबे के पिछले पखवाड़े दिए गए बयान से उजागर होता है. दुबे ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर कनिष्ठ अधिकारियों के तबादले और नियुक्तियों के नाम पर एक 'गोरखधंधा' चलाने का आरोप लगाया. उन्होंने बताया कि थाना स्तर के अधिकारी की नियुक्ति और तबादले के लिए औसतन 50,000 रुपए मांगे जाते हैं. मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभालने के बाद आजाद ने जब एक रात राजधानी के कुछ थानों का अचानक दौरा किया तो अधिकारियों ने उन्हें बताया कि राजनैतिक दखलंदाजी के कारण उन्हें अपना कामकाज करने में मुश्किल होती है.

ऐसे में अजब नहीं कि अपराधियों की बन आई है. हाल में संसद में विपक्ष और सत्ता दल दोनों के सदस्यों ने आरोप लगाया कि अपराधों के मामले में बिहार की हालत पंजाब से भी बदतर है. राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के बाद अपराध शाखा द्वारा पेश की गई एक विस्तृत गोपनीय रिपोर्ट ने भी पुलिस की 'कमजोरियों, अक्षमताओं और विफलताओं' को उजागर किया है. इसकें आंकड़े रोंगटे खड़े कर देने वाले थे. 1986 की तुलना में 1987 में हत्याओं के मामलों में 4.3 फीसदी वृद्धि हुई. यदि 1984 के आंकड़ों से तुलना की जाए तो यह वृद्धि 19 फीसदी थी.

लेकिन पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आजाद की सरकार उनकी उपलब्धियों को कम करके आंक रही है. उनका दावा है कि पिछले साल पुलिस मुठभेड़ों में 104 अपराधी मारे गए और 41,000 पकड़े गए, 2100 अवैध हथियार पुलिस ने जब्त किए.

बहरहाल, आजाद पुलिस ही नहीं दूसरे महकमों में भी उलटफेर कर रहे हैं. सक्षम अधिकारियों की तलाश में आजाद ने पूर्व मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे के प्रधान सचिव के.एस.एच. सुब्रमण्यम को शपथ ग्रहण के कुछ ही घंटे बाद हटा दिया. सुब्रमण्यम की जगह अपेक्षाकृत चुस्त माने जाने वाले एस.एन. चतुर्वेदी को बहाल किया गया है.

बिहार का अधिकारी वर्ग इस उलटफेर को सांस रोके देख रहा है क्योंकि उसे अभी और झटकों की आशंका है. बिहार को दुरुस्त करने के अपने प्रयासों में अगर आजाद जरा भी कमजोर पड़े तो राज्य के नौकरशाह खुश ही होंगे. वैसे भी आजाद के सामने चुनौतियां कठिन ही हैं.

—फरजंद अहमद

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तमिलनाडु

रोमांचक कथा

सांसद को 'खरीदने' की कोशिश

यह कहानी अगर फिल्म की होती तो जबरदस्त हिट होती. राजनैतिक हंगामे वाली इस कहानी में अपहरण, शराब और सौ-सौ के नोटों की गड्डियों की सप्लाई, एक सांसद द्वारा कच्छा पहने दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी चलाते भागते फिरना वगैरह-वगैरह सब है. पर हकीकत में भी यह कहानी कम नाटकीय नहीं.

पिछले पखवाड़े अन्नाद्रमुक (जानकी गुट) के सांसद एस. थंगराजू ने संसद में नोटों से भरा ब्रीफकेस खोला और घोषणा की कि जयललिता गुट ने उनका जमीर खरीदने के लिए यह रकम दी है. गहरे भूरे रंग के इस ब्रीफकेस में सौ-सौ के नोटों की गड्डियों में पांच लाख रुपए पड़े थे. इस घोषणा से अध्यक्ष बलराम जाखड़ और पूरा सदन भौंचक रह गया. विपक्ष के हंगामे के बीच थंगराजू ने दावा किया कि उन्हें अगवा कर लिया गया था और यह पैसा जयललिता के निजी सहायक ने उन्हें दिया.

इस घटना से साफ हो गया है कि अब जानकी और जयललिता गुट की लड़ाई की कोई सीमा नहीं रही है. 39 वर्षीय थंगराजू के अनुसार जयललिता गुट के सांसद पी. कोलंदैवेलू ने 22 फरवरी को उन्हें बातचीत के लिए अपने घर बुलाया, तभी से यह तमाशा शुरू हुआ. तिरुचि जिले के पेरांबलूर क्षेत्र के इस सांसद ने पुलिस से जो शिकायत की उसके अनुसार उन्होंने पहले तो इस बुलावे को ठुकरा दिया. पर बाद में राजधानी के नॉर्थ एवेन्यू इलाके में चक्कर लगाते समय उन्हें इस बातचीत के लिए मना लिया गया. कोलंदैवेलू के फ्लैट में उन्हें शराब पिलाई गई. बाद में थंगराजू ने कहा, "मुझे लगता है कि वह व्हिस्की थी. शराब मेरी कमजोरी है, जिसका उन लोगों ने फायदा उठाया."

उन्हें एक के बाद एक प्याला पिलाते हुए उनके मेजबान ने उनसे दो चिट्ठियों पर दस्तखत करने को कहा जिसमें उनके जयललिता गुट में आने की बात कही गई थी. लेकिन थंगराजू ने इनकार कर दिया. कुछ देर बाद उन्हें एमजीआर सरकार में मंत्री रहे एस. थिरुनावक्करासू से मिलने के लिए तमिलनाडु भवन ले जाया गया. उन्होंने भी इन पत्रों पर दस्तखत करने को कहा. थंगराजू का दावा है कि वे चूंकि लगातार इनकार ही करते रहे इसलिए उन्हें अगले दिन भर एक कमरे में बंद रखा गया और दारू पिलाई जाती रही.

मगर 24 फरवरी की सुबह वे वहां से 'भाग' निकले. तीसरे पहर फिर उन्हीं लोगों ने उन्हें पकड़ लिया. कोलंदैवेलू की अगुआई में जयललिता गुट के लोगों ने नशे में चूर थंगराजू को जबरन एक कार में बैठा लिया. उस समय वे सिर्फ कच्छा पहने हुए थे. इस घटना के दो चश्मदीद हैं— जानकी गुट के ही सांसद षण्मुगम और जगतरक्षकन, जिन्हें थंगराजू ने पहले की सारी बातें बता दी थीं. षण्मुगम ने कहा, "नशे में चूर थंगराजू कुछ बड़बड़ा रहे थे कि दूसरे लोगों ने उन्हें कार में ठूंसा और चलते बने. कुल तीन कारें थीं." अगर इस कहानी पर भरोसा करें तो इसके अनुसार फिर थंगराजू को विमान से मद्रास ले जाया गया और वहां उन्हें जयललिता के निवास पर ले जाकर यह रकम दी गई. षण्मुगम कहते हैं, "थंगराजू के पास हवाई जहाज के टिकट हैं जिनसे साबित होता है कि पूर्व मंत्री (थिरुनावक्करासू) भी उनके साथ गए थे."

लेकिन कोलंदैवेलू और ही किस्सा सुनाते हैं. उनका कहना है कि थंगराजू ने अपनी मर्जी से पाला बदला और 22 फरवरी को उनके निवास पर हुई जयललिता गुट के संसदीय बोर्ड की बैठक में भी हिस्सा लिया. सबूत के तौर पर वे उस बैठक की विवरण पुस्तिका दिखाते हैं जिस पर थंगराजू के हस्ताक्षर हैं.

कोलंदैवेलू कहते हैं कि थंगराजू ने उनके लेटरपैड पर ही जाखड़ को तार भेजा कि जगतरक्षकन और षण्मुगम ने उन्हें जानकी

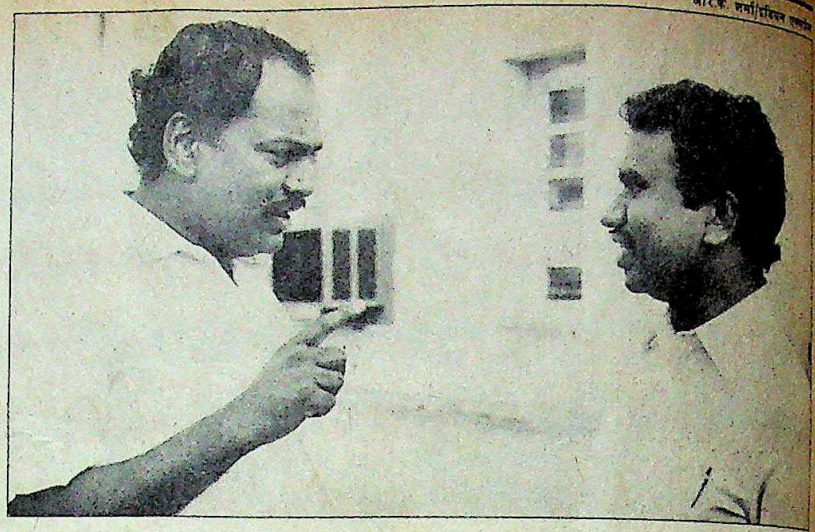

जगतरक्षकन के साथ थंगराजू (दाएं)

गुट में लाने के लिए उनका अपहरण करने की कोशिश की. वे बताते हैं, "जब जानकी गुट के लोगों ने हम लोगों पर अपहरण का आरोप लगाया तो गृहमंत्री बूटा सिंह ने भी इस तार को उद्धृत किया था. नॉर्थ एवेन्यू में उनका अपहरण कैसे हो सकता है; जहां कदम-कदम पर पुलिस चौकियां हैं?"

जयललिता गुट के नेता ने अपने विरोधियों पर सांसदों की खरीद-फरोख्त का आरोप लगाया. कोलंदैवेलू ने कहा, "उन्हीं लोगों ने तो इंका के विधायक भी खरीदने की कोशिश की थी. पूरा नाटक हमारी छवि खराब करने के लिए रचा गया था."

आरोपों-प्रत्यारोपों की बात छोड़ दें तो यह स्पष्ट है कि थंगराजू के आ जाने से जयललिता गुट को बहुत कम लाभ मिलता. लोकसभा में अन्नाद्रमुक के 12 सदस्य हैं. जिनमें थंगराजू समेत सात सदस्य जानकी गुट में और पांच जयललिता गुट में हैं. इसलिए जानकी गुट की सदस्य संख्या एक तिहाई से कम कराके उन्हें दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य करार दिलाने की कोशिश का सवाल नहीं उठता.

हां, संसद की विशेषाधिकार कमेटी द्वारा की जा रही जांच के बाद जरूर किसी न किसी गुट के सदस्य निष्कासित किए जा सकते हैं. लोकसभा में जनता संसदीय दल के नेता मधु दंडवते कहते हैं, "अगर रिश्वत देने की बात साबित हो गई तो यह सदन का अपमान होगा. अगर ये आरोप गलत साबित होते हैं तो संसद को गुमराह करने का अपराध और बड़ा हो जाता है." इसके बाद जयललिता-जानकी गुट की लड़ाई क्या रुख लेती है, इसकी कल्पना ही की जा सकती है.

—एस.एच. वेंकटरमनी और पंकज पचौरी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मध्य प्रदेश

संहारक अर्जुन

नरम रुख छोड़ दिया

अर्जुन सिंह ने काम करने की अपनी शैली में नाटकीय बदलाव कर लिया है. मुख्यमंत्री के रूप में अपने पिछले दौर की तरह विरोधियों को खुश रखने की नीति इस बार उन्होंने छोड़ दी है. पिछले महीने भोपाल पहुंचने के साथ ही वे विरोधियों के सफाए में जुट गए. उन्होंने बड़ी बेदर्दी से अपने राजनैतिक विरोधियों को ठिकाने लगाया है और पूर्ववर्ती मोतीलाल वोरा सरकार के पसंदीदा अधिकारियों को दूरदराज के इलाकों में भेज दिया है.

नतीजतन राज्य में पखवाड़े के अंदर भारी राजनैतिक और प्रशासनिक बदलाव हो गया है. अर्जुन सिंह की तीन साल की गैरमौजूदगी में भी जो अधिकारी उनके प्रति भक्तिभाव बनाए रहे, उन्हें बढ़िया जगहों पर बिठाया गया है. कुछ अधिकारियों को तो उन्होंने उनके 1985 वाले पदों पर लाने की भी कोशिश की है. उसी साल उन्हें राज्य छोड़कर जाना पड़ गया था.

शपथ ग्रहण के करीब तीन हफ्ते बाद 10 मार्च को उन्होंने प्रशासन में जो भारी उलटफेर किए उससे 20 आइएएस अधिकारी प्रभावित हुए. जैसी की उम्मीद की जा रही थी, पूर्व मुख्यमंत्री वोरा के करीबी माने जाने वाले मुख्य सचिव के.सी.एस. आचार्य को हटा दिया गया. उनकी जगह 1954 बैच के आइएएस मदनेश्वर शरण सिंहदेव को लाया गया है. अभी करीब तीन महीने बाद ही वे रिटायर होने वाले हैं. इनके अलावा सचिव स्तर के कई महत्वपूर्ण अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है.

लेकिन यह फेरबदल उतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता जितना कि राजनैतिक उलटफेर. इस उलटफेर में अर्जुन सिंह रेल राज्यमंत्री माधवराव सिंधिया के समर्थकों के प्रति कुछ ज्यादा ही नाराज दिखते हैं. तत्कालीन ग्वालियर राजघराने के इस उत्तराधिकारी के वोरा मंत्रिमंडल में सिर्फ दो समर्थक थे. इनमें से एक, शिव प्रताप सिंह को इस बार बाहर कर दिया गया है. दरअसल अर्जुन सिंह ने सबसे पहले जो फैसले किए उनमें शिव प्रसाद सिंह के बेटे और गुना के पुलिस अधीक्षक एल.एम. तिवारी के खिलाफ साल भर पुराने बलात्कार के मामले की जांच दुबारा शुरू करना भी शामिल है. तिवारी भी सिंधिया के प्रिय पात्र हैं. सिंधिया के प्रबल प्रतिद्वंद्वी हनुमंत सिंह को मंत्री बनाकर उन्होंने रेल राज्यमंत्री को एक और शह दे दी है.

वोरा समर्थकों की स्थिति भी कोई बेहतर नहीं रही है. अर्जुन सिंह ने वोरा मंत्रिमंडल के 21 में से 13 सदस्यों को बाहर कर दिया. वैसे निकाले गए कई मंत्रियों को ईमानदार माना जाता था जबकि आठ नए मंत्रियों में से शायद ही

अर्जुन और सिंधिया: अपने-अपने दांव

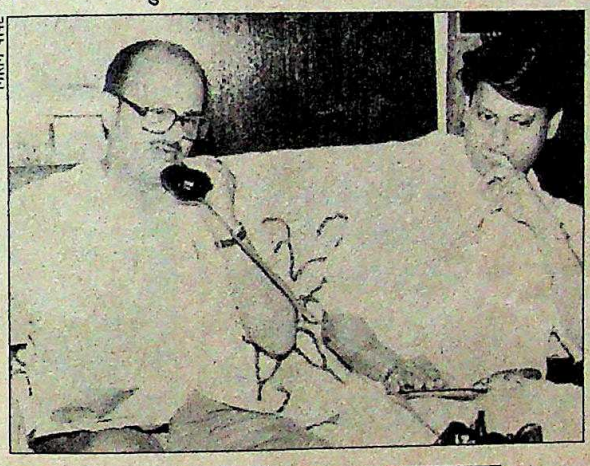

अर्जुन सिंह ने अपनी शैली बदल दी है. विरोधियों को खुश रखने की नीति इस बार उन्होंने छोड़ दी है. नतीजतन पार्टी में असंतोष उभरने लगा है

किसी की छवि काम करने वाले की है. यही वजह है कि 17 विभाग मुख्यमंत्री ने अपने ही पास रख लिए हैं. मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, गुप्तचर विभाग के मुखिया और कपड़ा निगम के अध्यक्ष समेत करीब 50 अधिकारी बदल दिए गए हैं.

और इन सबका जो नतीजा होना था वही हुआ भी. तमाम नाराज नेता पार्टी आलाकमान के पास शिकायतें लेकर पहुंचने लगे हैं. अर्जुन सिंह ने अपने तुगलक रोड निवास पर राज्य के इंका सांसदों को जो भोज दिया उसमें 52 में से 23 सांसद आए ही नहीं. प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और अब केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याणमंत्री वोरा भोज खत्म होने के बाद पहुंचे. सिंधिया भी भोज में गए. पर इन दोनों के अधिकांश समर्थक सांसद नदारद रहे.

समर्थकों की छुट्टी करने के अलावा अर्जुन सिंह ने वोरा को और तरह भी परेशान किया है. वोरा सरकार ने 23 फरवरी को पेश करने के लिए जो बजट बनाया उसे उन्होंने खारिज कर दिया. नया बजट तैयार करने के लिए विधानसभा का बजट सत्र 20 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया. वोरा सरकार द्वारा तैयार बजट की छपाई शुरू हो गई थी जिसे रोक दिया गया.

इसके अलावा वे पिछली सरकार द्वारा अंतिम कुछ हफ्तों में की गई नियुक्तियों, तबादलों और कार्यकाल बढ़ाने के फैसलों की समीक्षा भी कर रहे हैं. अर्जुन सिंह द्वारा व्यक्तिवाद को बढ़ावा देने के खिलाफ इंका में नाराजगी पनप रही है. नाराज इंकाई कहते हैं कि पार्टी के दूसरे धड़ों को खफा करके इंका विपक्ष का एकजुट होकर सामना नहीं कर पाएगी. अर्जुन सिंह को अगले चुनाव को ध्यान में रखकर मध्य प्रदेश भेजा गया है पर उनकी ऐसी कार्रवाइयों से यह मकसद पूरा नहीं होगा.

यह सब करके अर्जुन सिंह विपक्षी दलों का हित साध रहे हैं. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुंदरलाल पटवा कहते हैं, "अर्जुन सिंह की वापसी से हमारा काम आसान हो गया है." विपक्ष इंका में मची उथल-पुथल को हसरत भरी निगाहों से देख रहा है. अर्जुन सिंह को बहुत जल्दी ही विपक्ष का मुकाबला करना पड़ेगा क्योंकि वे अभी सांसद हैं और उन्हें विधानसभा में पहुंचने के लिए चुनाव लड़ना होगा. शासक दल के लिए सुरक्षित माने जाने वाले रायगढ़ जिले के निर्वाचन क्षेत्र खरसिया के विधायक ने इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री के लिए पहले ही सीट खाली कर रखी है. लेकिन संयुक्त उम्मीदवार खड़ा करने की योजना बना रहे विपक्षी दल भी कमर कसे हैं कि अर्जुन सिंह को आसानी से मैदान मारने न दें. जनमोर्चा नेता विद्याचरण शुक्ल कहते हैं, "अर्जुन सिंह के लिए यह लड़ाई आसान नहीं होगी."

अर्जुन सिंह जिस तरह पार्टी में धड़ेबाजी चलाने में लगे हुए हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि उनकी अपनी पार्टी के ही कई लोग उनकी इस लड़ाई को मुश्किल बना देंगे.

—नरेंद्र कुमार सिंह

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मणिपुर

तख्ता पलट गया

कीर्शिंग चुपचाप नहीं बैठेंगे

जन्मदिन पर इससे बढ़िया तोहफा नहीं हो सकता था. पिछले पखवाड़े 47 बरस के हुए केंद्रीय रसायन राज्यमंत्री राजकुमार जयचंद्र सिंह को मणिपुर के मुख्यमंत्री की गद्दी पर आसीन कर दिया गया. उन्हें मुख्यमंत्री बनाने में खुद प्रधानमंत्री ने दिलचस्पी ली.

लेकिन फेरबदल उतनी आसानी से नहीं हो पाया. 60 सदस्यीय विधानसभा में इंका के 39 विधायकों में से 25 का समर्थन रिशांग कीशिंग को हासिल था इसलिए वे गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं थे. फेरबदल करवाने गए केंद्रीय गृहमंत्री बूटा सिंह यह जानकर तो सन्न ही रह गए कि कीशिंग ने मुख्यमंत्री पद से हटने से इनकार कर दिया है. उत्तर-पूर्व में पार्टी मामलों की देखरेख करने वाले और ऑस्कर फर्नांडीस और संतोषमोहन देव की कोशिशें भी नाकाम रहीं. अंत में राजीव को खुद कीशिंग को फोन करना पड़ा. कीशिंग पिछले आठ सालों से लगातार सत्ता में हैं.

अंत में 4 मार्च की मध्य रात्रि को इंका विधायक दल की बैठक होने से ठीक पहले कीशिंग ने इस्तीफा दे दिया. जयचंद्र सिंह 'सर्वसम्मति' से नेता चुन लिए गए. उनके नाम का अनुमोदन खुद कीशिंग ने किया. कीशिंग ने तल्खी से कहा, "मैंने कोई गलत काम नहीं किया. यह नाइंसाफी है. कोई आपसी मतभेद भी तो नहीं थे जिनके बदौलत मुझे हटा दिया गया."

हालांकि मणिपुर में असंतुष्टों की मौजूदगी कोई नई बात नहीं है लेकिन कीशिंग के जाने की वजहें कुछ और ही हैं. पिछले साल असंतुष्टों ने राजीव को एक ज्ञापन दिया जिसमें कीशिंग मंत्रिमंडल पर भ्रष्टाचार और अकुशलता के आरोप लगाए गए थे. इसके बाद मुख्यमंत्री के बदलाव को लेकर असंतुष्ट पिछले दो महीने से नई दिल्ली में डेरा डाले हुए थे.

लेकिन कीशिंग पर गाज इसलिए गिरी क्योंकि बगावत से त्रस्त राज्य में वे सेना और अर्द्धसैनिक बलों के साथ निभा नहीं पा रहे थे. इसी से राज्यपाल जनरल कृष्ण राव से भी उनकी पटरी नहीं बैठ रही थी.

रजत बसु

जयचंद्र सिंह (बाएं) और कीशिंग

जयचंद्र सिंह को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कीशिंग का पत्ता उन्हें 25 विधायकों के समर्थन के बावजूद काट दिया गया

समझा जाता है कि राव ने केंद्र को लिखा था कि कीशिंग और उनकी सरकार ने सुरक्षा बलों के लिए तमाम तरह की मुश्किलें खड़ी कर रखी हैं. कई बार कीशिंग और उनके कुछ मंत्रियों पर नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (एनएससीएन) के गुरिल्लों से रिश्ते रखने के आरोप भी लगे.

पिछले साल के अंत में स्थिति तब गंभीर हो गई जब गुरिल्लों के एक हमले में 9 सुरक्षा कर्मचारी मारे गए और उसके बाद सुरक्षा बलों को ग्रामीणों को प्रताड़ित करने का दोषी ठहराया गया. आरोप है कि उन्होंने असम राइफल्स की खिलाफत के लिए लोगों को उकसाया. कीशिंग कहते हैं, "अर्द्धसैनिक बल और राज्यपाल पिछले दो सालों से मेरी सत्ता पलटने की कोशिशें कर रहे थे."

पार्टी में कीशिंग असंतुष्टों से ज्यादा शक्तिशाली थे. असंतुष्टों का नेतृत्व पूर्व उपमुख्यमंत्री इरेनबाम तोंपोक सिंह कर रहे थे और उनकी पीठ पर विधानसभा अध्यक्ष ए. अंगू का भी हाथ था. इसका असर प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ रहा था और फिर दिसंबर में चुनाव भी होने हैं इसलिए पार्टी आलाकमान पार्टी की छवि बदलने के लिए उत्सुक हो उठा था.

लेकिन जयचंद्र सिंह क्या चुनाव में पार्टी को जिता सकेंगे? अप्रैल 1984 में राज्यसभा के लिए चुने गए और इसके बाद से राजीव सरकार में मंत्री रहे सिंह ने मणिपुर से कोई चुनाव नहीं जीता है. वहां उनका कोई जनाधार भी नहीं है. 1980 में सागोलबंद विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने पर उन्हें केवल 450 वोट ही मिल पाए थे. राज्यसभा में जाने से पहले वे इंका की मणिपुर इकाई के महासचिव थे.

हालांकि जयचंद्र सिंह की क्षमताओं को लेकर इंका नेता परेशानी में पड़ सकते हैं. लेकिन एक बात तो तय है कि नए मुख्यमंत्री का रवैया अपनी टीम बनाने के बारे में एकदम स्पष्ट रहा है. उन्होंने कीशिंग के 14 मंत्रियों में से सिर्फ दो को मंत्रिमंडल में शामिल किया और कीशिंग के कट्टर विरोधियों—तोंपोक सिंह को गृह और राजस्व तथा ललित सिंह को वित्त जैसे प्रमुख मंत्रालय सौंप दिए. जयचंद्र सिंह कहते हैं, "मैं अपनी नई टीम का इस्तेमाल राज्य के विकास, नशाखोरी की रोकथाम, प्रशासन को पटरी पर लाने और बड़े पैमाने पर लघु उद्योगों का जाल बिछाने में करूंगा."

तोंपोक सिंह सेना और अर्द्धसैनिक बलों के साथ मधुर संबंधों के लिए जाने जाते हैं. इसलिए उम्मीद है कि मणिपुर में पहले दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं नहीं होंगी. जैसी लेकिन कीशिंग बहुत दिनों तक शांत नहीं रह सकते और 12 पूर्व मंत्रियों के समर्थन के बूते वे जयचंद्र सिंह मंत्रिमंडल के लिए परेशानियां पैदा कर सकते हैं. इसके अलावा नए मुख्यमंत्री को अलगाववादी ताकतों से भी निबटना होगा. कुल मिलाकर नए मुख्यमंत्री की नींद हराम ही रहेगी.

—रमेश मेनन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दूसरा दांडी मार्च

(प्यारेलाल द्वितीय की डायरी से)

12 मार्च 1988: आज का दिन तो ऐतिहासिक महत्व का दिन है. पिछले कुछ हफ्तों से हम इस महान घटना की तैयारियों में व्यस्त थे. हर बार की तरह आज भी गांधी जी ही आकर्षण केंद्र रहे. भारत की दूसरी आजादी के सभी महान राष्ट्रीय नेता बापू के कमरे में आ-जा रहे हैं. रोमी जी, अमिताभ जी, गोपी जी, शारदा जी, सैम जी, सुमन जी, फ़ोतेदार जी, सभी आखिरी पल में अपने प्रिय नेता, पथ प्रदर्शक बापू से निर्देश लेने पहुंच रहे हैं.

पर इन सभी नेताओं को कुटिया के बाहर ही इंतजार करना पड़ा क्योंकि बापू आजकल मौन व्रत धारण किए हुए हैं. मौन व्रत के दौरान वे कुछ नहीं बोलते, केवल वीडियो के सामने ध्यान-मग्न होकर बैठे रहते हैं. उस पर माइकल जैक्सन जी, टीना टर्नर जी और ब्रूस स्प्रिंगस्टीन जी के ताजातरीन रॉक भजनों की फिल्म चल रही है. गांधी जी अपने शिष्यों से हमेशा कहा भी करते हैं, "जब मैं पॉप संगीत के इन दिग्गजों को सुनता हूं, मेरा दिल वल्लियों उछल पड़ता है."

अब बापू के व्रत तोड़ने का समय सन्निकट है. हर कोई इस जश्न में शामिल रहेगा ही. कुछ समय से बापू रोजाना तीन बार नियमित रूप से व्रत करते आ रहे हैं. सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर को लंच और रात को डिनर से पहले उनका व्रत रहता है.

इतने कठोर व्रत के बाद उन्हें विशेष किस्म का पौष्टिक भोजन मिलना ही चाहिए. सोनिया जी और रोमी जी उनकी भोजन की सामग्रियों की सूची बनाती हैं. उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि बापू को कौन-कौन सी चीजें प्रिय हैं और किन चीजों से वे परहेज करते हैं. इनमें अक्सर केविआर, भुनी हुई सामन मछली, पनीर और कई बार लिट्ट चॉकलेट सरीखा हल्का भोजन ही होता है. साथ में बोर्डियो की शराब या शैंपेन भी होती है.

सभी नेता गांधी जी की आहार संबंधी सनक पर आसक्त हैं. उनका विदेशी भोजन आता भी तो दूर-दूर से, दुनिया के कोने-कोने से है. हल्के खाने के बाद गुफ्तगू का दौर शुरू होता है. इसमें सभी नेता गांधी जी से देश और दुनिया की ताजा गतिविधियों, मसलों पर चर्चा करते हैं, उनसे सलाह मांगते हैं.

रोमी जी ने पूछा, "बापू! पिछले पखवाड़े हमें दिल्ली में स्वतंत्रता की दौड़ क्यों लगानी पड़ी?"

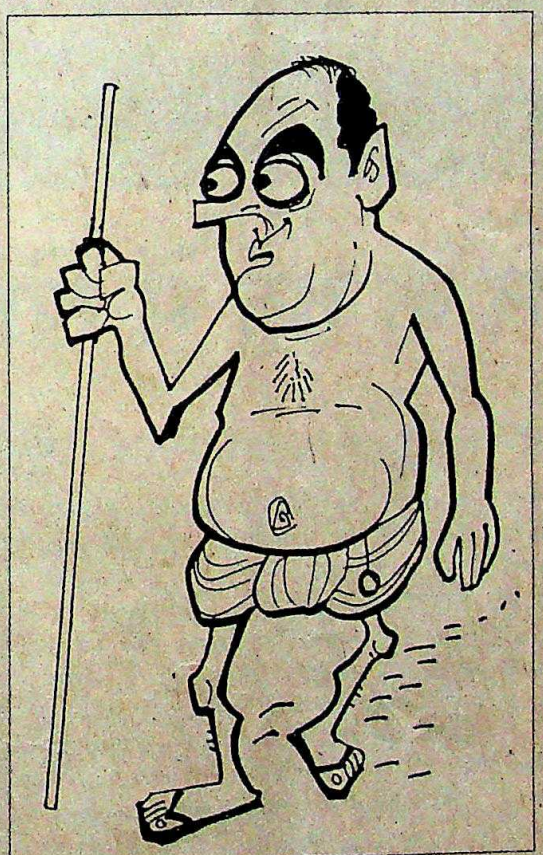

गांधी जी कताई में खोये हुए थे. वे छोटे कंप्यूटर के एक खेल में डायल घुमा रहे थे, मानो चरखा कात रहे हों. यह खेल सैम जी ने उन्हें भेंट किया था. सिर उठाकर आहिस्ते से वे बोले, "अतीत से आगे निकलने की खातिर ही हमें यह दौड़ लगानी पड़ी."

"पर बापू," अमिताभ जी बोल पड़े, "हम अतीत से आगे निकल भी गए तो क्या होगा?"

गांधी जी खेलते हुए भी सोच में पड़ गए. आखिर मौन भंगकर बोले, "अतीत से आगे निकलकर हम 21वीं सदी में पहुंच जाएंगे."

कमरे में फुसफुसाहट होने लगी. फोतेदार जी अपनी उत्कंठा न रोक पाए. कहने लगे, "मगर बापू! हमें साबरमती नदी के तट पर किस मकसद से बुलाया गया है?"

"इसलिए कि यही कुछ कर दिखाने का वक्त है," बापू सख्ती से बोले, "हम सभी को एक साथ मिलकर काम करना है. अगर वहां शूटिंग भी शुरू हो जाए तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग नर्वस नहीं होंगे बल्कि...."

लेकिन शूटिंग के जिक्र पर शारदा जी अभी से नर्वस होने लगे. पूछने लगे, "बापू! यह तो बताइए, शूटिंग करेगा कौन—पुलिस या सेना?"

"आपको तो यह पता होना ही चाहिए," बापू बड़ी नरमी से बोले, "कैमरामैनों के अलावा और कौन शूटिंग करेगा!"

पर गोपी जी संतुष्ट नहीं हुए. पूछ बैठे, "पर बापू, एक साथ काम करने से हासिल क्या होगा?"

"आत्मनिर्भरता सीखेंगे," गांधी जी का जवाब था, "दुनिया जानेगी कि सिर्फ रिचर्ड एटनबरो ही भारत की आजादी की खातिर नहीं लड़ा."

तभी एक पार्टी कार्यकर्ता कमरे में आया. एक ही सांस में बोला, "बापू! हर कोई आपके इंतजार में है! लोगों की भीड़, अखबारों के संवाददाता, फोटोग्राफर सभी पहुंच चुके हैं."

गांधी जी उठ खड़े हुए. गुच्ची सैंडिल पहनते हुए बोले, "तो आओ, हम चलें."

हर कोई उनके नक्शेकदम पर चलने लगा. ऐसे शुरू हुआ हमारा दांडी मार्च. बाकी तो सारा इतिहास है....

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सभी फोटो: भवन वि

आरमेनियन

विस्मृति के गर्त में खोए लोग

न वह ऐश्वर्य रहा, न मान न सम्मान, रही सिर्फ यादें

*कोचीन में यहूदी हैं, तो बंबई में पारसी. भारत के गिने-चुने कस्बों और शहरों में रह रहे विदेशी समुदायों की अपनी अलग पहचान है. कलकत्ता में बसे आरमेनियन भी ऐसे ही हैं. कभी शहर के व्यापार-धंधे पर हावी रहा यह तबका अब विस्मृति के गर्त में चला गया है. **सुरजीत दासगुप्त** की एक रिपोर्ट:*

1921, कलकत्ता का रेसकोर्स: दौड़ते घोडों के लक्ष्य नजदीक पहुंचने के साथ-साथ बाजी लगाने वालों और सट्टेबाजों का शोर-शराबा कर्णकटु हो उठता है. रेस खत्म होते ही बाजी लगाने वाले लोग प्रिंस ऑफ वेल्स कप के विजेता 'गेटवे गेट' के मालिक जोहान्नेस कारापाएट गाल्स्टॉन को घेर लेते हैं.

1988, आरमेनियन चर्च का उजाड़ कब्रिस्तान: उपेक्षित गाल्स्टॉन की कब्र लापरवाह शहर की भागमभाग और भीड़-भाड़ से दूर शांत और खामोश.

आधी शताब्दी पहले गाल्स्टॉन कलकत्ता के लगभग 2000 समृद्ध आरमेनियन समुदाय का प्रतीक हुआ करता था. वह 'गेटवे गेट' का ही मालिक नहीं था, बल्कि उसके पास और भी 100 घोड़े थे. शहर की लगभग 350 इमारतें उसकी मिल्कियत हुआ करती थीं. आज गाल्स्टॉन जीवित नहीं है, उसके बच्चे दूसरी जगहों को चले गए हैं, शहर में आरमेनियनों की संख्या 200 से भी कम रह गई है और कभी गर्व से सिर उठाकर चलने वाले इस समुदाय के लोग आज दीनहीन हालत में पहुंच गए हैं.

उनमें अपना अस्तित्व लुप्त होते जाने का भाव प्रबल होता जा रहा है. जहां उन्होंने कभी अपना बसेरा बनाया, वहां उन्हें कोई भविष्य नजर नहीं आता

16वीं शताब्दी में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की तरह वे भी व्यापारी के रूप में आरमेनिया से यहां बसने आए थे (आरमेनिया अब ईरान, तुर्की और सोवियत संघ में विभाजित है). वे शुरू में तो सूरत और बंगाल के चिनसुड़ा और चंद्रनगर में बसे. उनमें से कुछ मद्रास भी जा पहुंचे. यहां तक कि आगरा और लखनऊ में भी आरमेनियनों की बस्तियां आबाद हो गईं. सूरत में तो उनका अपना कब्रिस्तान भी है. लेकिन ज्यादातर आरमेनियनों ने कलकत्ता को ही अपना बसेरा बनाना पसंद किया.

शहर के फैशनेबल इलाके रसेल स्ट्रीट में केनिलवर्थ होटल चला रही जॉयस पही आज भी गर्व से कहती हैं, "कलकत्ता अंग्रेजों ने नहीं, हमने बनाया है." यदि पही की बातों पर यकीन करें तो आरमेनियनों का एक समय आधे शहर पर अधिकार था. अंग्रेजों

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कब्रों की मरम्मत का निर्देश देते सारकीज (ऊपर बाएं); आरमेनियन कॉलेज (ऊपर) और एक आरमेनियन परिवार : अलग पड़ता समूह

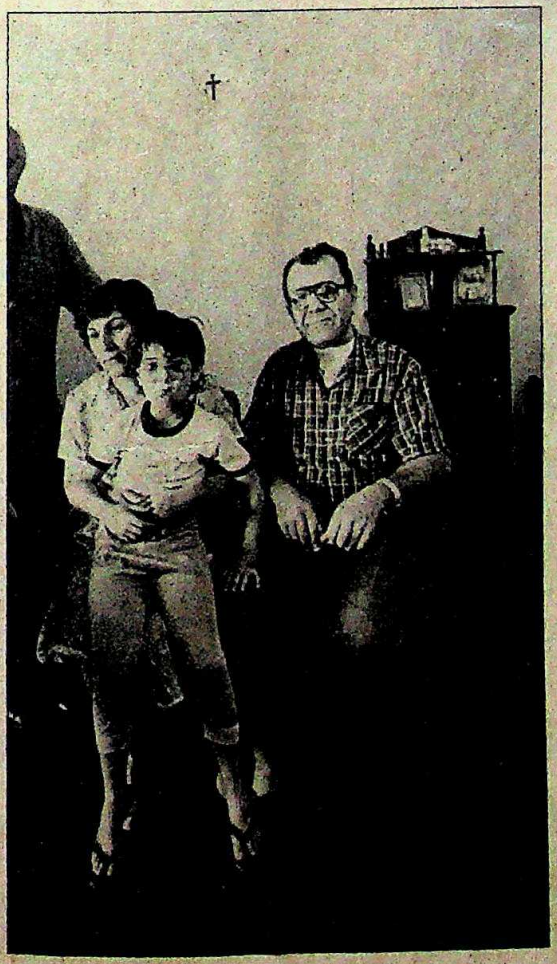

ग्रैंड होटल, बहुत से छोटे होटल और व्यावसायिक केंद्र उनके अधिकार में थे. शहर के व्यवसाय पर मारवाड़ियों का कब्जा होने से पहले पूर्वी भारत के व्यापार खासकर नील, लाख, खनन, इंजीनियरिंग, जहाज परिवहन और निर्माण में अंग्रेजों के बाद आरमेनियन दूसरे नंबर पर थे.

किसी समय समृद्ध रहे इस समुदाय के पास आज क्या बाकी रह गया है, इसका अंदाज बुजुर्गों के लिए बने पॉल नैदर्स होम को देखकर लगाया जा सकता है. रविवार की शाम को छड़ियां लिये, दूसरों के सहारे या निपट अकेले चलते 65 की उम्र पार कर चुके कुछ आरमेनियन बुजुर्ग धीरे-धीरे नाजरथ चर्च की ओर जाते दिखते हैं. वे कब्रों से घिरे चर्च का प्रांगण पार करते हैं. चर्च की धूल जमी काच की खिड़कियां, छत पर लटकते तेल से जलने वाले दिये और दीवारों पर लटकी बेरंग होती तस्वीरें अतीत की याद दिलाती हैं. आरमेनियन कॉलेज के 61 वर्षीय प्राचार्य वाहान पोलाडिन कहते हैं, "हम समाप्त हो रहे हैं. समुदाय का कोई भविष्य दिखाई नहीं देता."

अपने अच्छे दिनों में यह समुदाय केवल आरमेनियन कॉलेज ही नहीं बल्कि आरमेनियन स्पोर्ट्स क्लब (अपनी बेहतरीन रग्बी टीम के लिए मशहूर) और आरमेनियन क्लब भी चलाता था. लेकिन अब कॉलेज में पढ़ने लायक विद्यार्थी नहीं मिलते इसलिए कॉलेज स्कूल में तब्दील हो गया है. ईरान से कुछ नए आरमेनियनों के आने के बावजूद (पश्चिम के रास्ते से), इस कॉलेज में मुश्किल से आठ से 18 वर्ष के 100 विद्यार्थी हैं और दो आरमेनियन प्राध्यापक (बाकी ज्यादातर बंगाली हैं).

कलकत्ता मैदान में बने स्पोर्ट्स क्लब के सुनसान क्लब हाउस में इन दिनों चार वृद्ध लोग गपशप करते रहते हैं. हालांकि आरमेनियन कॉलेज के छात्रों ने किसी भी तरह जोड़-तोड़कर रग्बी टीम बना रखी है लेकिन स्पोर्ट्स क्लब के सदस्यों की संख्या घटकर मात्र 12 रह गई है. आरमेनियन क्लब भी इसके नजदीक ही है. अभी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हाल-हाल तक बूढ़े और जवान यहां या तो बिलियर्ड्स खेला करते थे या बैठकर गप्पें लड़ाया करते थे.

आजादी मिलने के बाद उनकी संख्या, हैसियत और व्यावसायिक परिस्थिति में गिरावट आनी शुरू हुई. आरमेनियन लोगों ने ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन किया था और ज्यादातर आरमेनियनों को स्वतंत्र भारत में कोई भविष्य नजर नहीं आता था. खास तौर पर नौजवान आरमेनियन पश्चिमी देशों में जाना चाहते थे. कइयों ने बाहर जाने का जुगाड़ भी जमा लिया.

बाकी बच रहे ज्यादातर लोगों ने पाया कि नील और लाख जैसे जिन धंधों से वे कभी संपन्नता की मंजिलें चढ़े वे अब खत्म हो चुके हैं. खदानों का राष्ट्रीयकरण हो गया और बाद में कलकत्ता के व्यापार पर मारवाड़ी काबिज हो गए.

व्यापार हाथ से निकल गया, नौजवान भी साथ छोड़कर बाहर चले गए और बंगाली अभिजात्य वर्ग से रिश्ते भी धीरे-धीरे खत्म हो गए. नतीजतन यह समुदाय धीरे-धीरे विस्मृति के गर्त में खोता चला गया. बूढ़े बुजुर्ग अब अजनबियों से भरे इस परिचित शहर में मानो मृत्यु की प्रतीक्षा में बैठे हैं.

एक समय खानपान का इंतजाम करने के लिए मशहूर रहे 82 वर्षीय जॉर्ज डेविड जब अपने बेटों के इंग्लैंड चले जाने के वाकये को याद करते हैं तो उनका एकाकीपन छिपाए नहीं छिपता. अपने सपनों के मुल्क में जा बसे उनके बेटे तो चिट्ठी लिखकर खोज-खबर भी नहीं लेते कि उनके पिता जिंदा हैं या मर गए.

पॉल चैटर्स होम के कर्ता-धर्ता 65 वर्षीय चार्ल्स सारकीज हैं. सारकीज अपना ज्यादातर वक्त आरमेनियनों की कब्रों की मरम्मत करने वाले मजदूरों को निर्देश देते हुए बिताते हैं. इन कब्रों में से ज्यादातर पर लगा संगमरमर चोरी चला गया है. वे अपने बच्चों के पास आस्ट्रेलिया नहीं गए. वे कहते हैं, "बच्चों के आफिस चले जाने के बाद मैं वहां क्या करूंगा. मैं वहां भी अकेला ही रह जाऊंगा. यहां मैं कुछ तो सामाजिक काम कर रहा हूं." कभी बहुत संपन्न रहे आरमेनियन परिवार के एक 70 वर्षीय सदस्य जॉर्ज अपकार भी यहीं रहते हैं. वे फोटो खींचे जाने से पहले कपड़े बदलकर आने पर जोर देने लगे.

पॉल चैटर्स होम इसके संस्थापक के नाम पर ही बना है. उन्होंने 1950 में इसकी स्थापना की थी. इस होम में हरा-भरा बगीचा और साफ-सुथरे कमरे बने हुए हैं. यहां का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम साप्ताहिक वीडियो के प्रदर्शन का होता है. पर 74 वर्षीय बी. माभियत की शायद उसमें कोई दिलचस्पी नहीं. वे अपने कमरे में बिस्तर पर अकेली बैठी खिड़की से बाहर दूर कहीं देख रही हैं मानो ईश्वर के बुलावे का इंतजार कर रही हों. वे बातचीत करने से भी इनकार कर देती हैं.

समुदाय को एकजुट और उनकी पहचान

एक सामुदायिक जमावड़ा

कायम रखने का बड़ा सूत्र पास का चर्च ही है. चर्च बुजुर्ग और गरीब आरमेनियनों की सहायता के साथ-साथ स्कूली बच्चों के लिए भी धन उपलब्ध कराता है. यह पैसा उन अमीर आरमेनियनों के पास से हमेशा आता रहता है जो देश छोड़कर चले गए हैं.

दूसरे समुदायों में ब्याह करने वाले आरमेनियन युवाओं पर चर्च की कोपदृष्टि भी पड़ती है और आर्थिक ताकत के कारण चर्च अपनी बात मनवाने में भी समर्थ रहता है. आरमेनियनों की पहचान बनाए रखने के लिए आरमेनियन कॉलेज में आज भी आरमेनियन इतिहास, भाषा और धर्म की पढ़ाई पर जोर दिया जाता है.

लेकिन कोई भी देख सकता है कि स्कूल के स्तर में गिरावट आ रही है. यहां प्रवेश के लिए कोई प्रतियोगी परीक्षा नहीं होती क्योंकि संख्या काफी कम होती है. ऐसे गैर-प्रतियोगी वातावरण में युवाओं की क्षमताएं उभर नहीं पातीं.

इस उम्मीद में कि बच्चों का भला होगा, बहुत से आरमेनियन अभिभावक अपने बच्चों को दूसरे स्कूलों में भेजना पसंद करते हैं. ऐसी ही एक मां, जिसके बेटे की शिक्षा भारत और इंग्लैंड में हुई है, कहती हैं, "आरमेनियन भाषा और इतिहास सीखने में बहुत समय लग जाता है. ऐसे में बच्चे उनकी कामयाबी के लिए जरूरी दूसरे विषयों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, जबकि दुनिया में कामयाबी के लिए दूसरे विषयों का ज्ञान भी जरूरी है."

हांगकांग में हीरों का व्यापार कर रहे एक आरमेनियन से दान मिलने के कारण इस स्कूल को नया जीवन मिल गया है. ईरान से कई नए लड़के भी यहां पढ़ने के लिए आ गए हैं.

कुछ आरमेनियनों ने अब भी प्रभावशाली बंगाली समुदाय से संपर्क बनाए रखे हैं लेकिन धीरे-धीरे ये संपर्क सीमित और औपचारिक होते जा रहे हैं. कुछ आरमेनियन परिवारों के रिश्ते अब भी उन बंगाली परिवारों से हैं जिनके साथ लंबे समय तक उनके व्यापारिक संबंध रहे थे.

लेकिन ज्यादातर कलकत्तावासियों के लिए आरमेनियन आज एक अपरिचित समुदाय बनकर रह गया है. आरमेनियन कॉलेज के पास रहने वाले एक एकाउंटेंट निशिथ गुप्ता कहते हैं, "हमें ईरानियों जैसे कुछ लड़के तो जरूर दिखाई देते हैं लेकिन स्कूल के उस भारी-भरकम दरवाजे के पार क्या होता है पता नहीं."

आरमेनियनों के बारे में ज्यादातर बंगालियों की अनभिज्ञता अकारण नहीं है. कभी शहर के सामाजिक जीवन पर छाए रहने वाले आरमेनियन आज सिर्फ अपने में सिमटकर रह गए हैं. जॉयस पर्डी कहती हैं, "हमारा समुदाय छोटा है और हमें अपनी पहचान बनाए रखनी है."

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

टाटा की ओर से टाइटन क्वार्ट्ज़

ऐसी घड़ियों के लिए अब आपको यूरोप, जापान अमरीका या किसी ड्यूटी-फ़्री दुकान में जाने की ज़रूरत नहीं. इन्हें आपके शहर में पेश कर रहे हैं टाइटन.

आकर्षक, पतली और बहुत बारीक इंजीनियरिंग से सजी संवरी टाइटन घड़ियां दुनिया की सबसे अच्छी घड़ियों की बराबरी में आ सकती हैं.

टाइटन की **अंतर्राष्ट्रीय किस्मों** में ऐसी घड़ी ज़रूर है, जो आपके लिए बिल्कुल सही है. शान और रूप का अनोखा संगम. लेदर के साथ गोल्ड वाली टाइटन या सिर्फ़ गोल्ड की चमकदमक वाली लीजिए, अगर सिर्फ़ स्टील वाली चाहिए तो वो भी हाज़िर. या फिर आजकल के ज़माने वाली कोई और टाइटन चुन लीजिए.

महिलाओं के लिए निहायत खूबसूरत डिज़ाइनों वाला कलेक्शन, जिसमें स्टाइल, वरायटी और रंगों पर विशेष नज़र रखी गई है. इतना ही नहीं, टाइटन के पास लेडीज़ डेट और डे-डेट घड़ियों की सबसे बड़ी श्रेणी मौजूद है.

टाइटन क्वार्ट्ज़ अपनी बराबरी में आ सकनेवाली सबसे अच्छी, चाबी से चलने वाली या आटोमैटिक घड़ियों से **६० गुना ज़्यादा सही है.**

हर टाइटन क्वार्ट्ज़ पर क्वालिटी और विश्वसनीयता की **टाटा गारण्टी है.**

अपने शहर की किसी अच्छी घड़ी की दुकान में जाइए और पसंद कीजिए कोई टाइटन क्वार्ट्ज़ अपने लिए या अपनों के लिए.

TITAN
QUARTZ

अपने लिए, अपनों के लिए

शानदार स्टाइल वाली टाइटन घड़ियां केवल रु. ३६२ से रु. ११३७ (बिक्री कर और स्थानीय कर अलावा) तक में मिलती हैं.

टाइटन वाचेज़ लिमिटेड
सोना टावर्स, ७१ मिलर रोड, बंगलोर ५६० ०५२.

OBM/1901/HN Rev

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

हालड स कहा ज़्यादा रामाचक... 'हालड'!

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

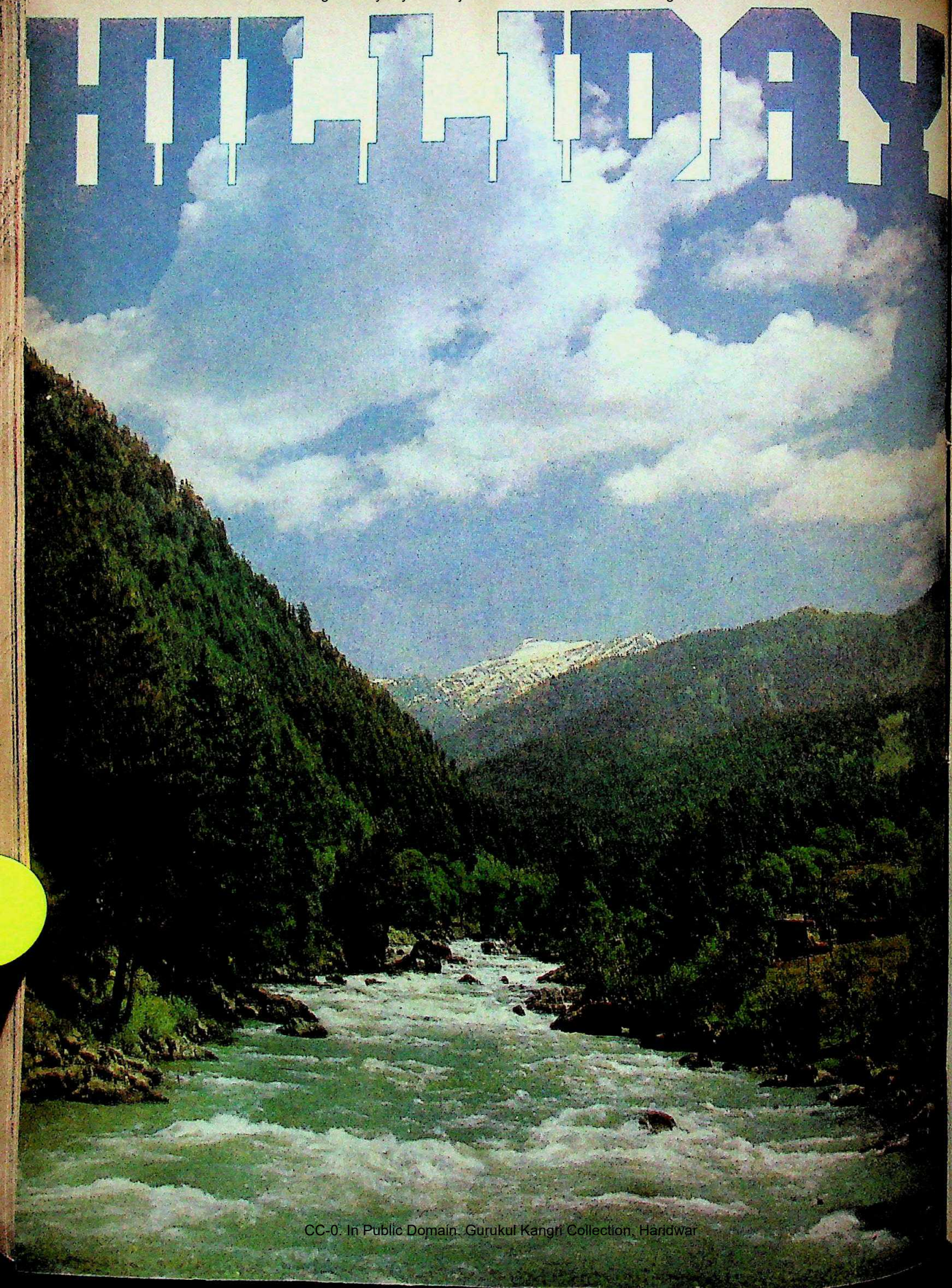

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रकृति की बाहों में आमंत्रण-स्वास्थ्य और आनंद भरे क्षण

पर्वतों से आती ठंडी, सुहानी हवा. पेड़-पत्तों से छन-छन कर गुज़रती... फूलों की खुशबू चुराती. आपको ताज़गी से सराबोर करती. वर्षभर— किसी भी समय... हर समय !

'हिलिडे' का यही है अनोखा आनंद! कितना सुखद. बेहद ताज़गी भरा. कायाकल्प कर देने वाला. क्योंकि यह आपको ले चले धरती से आकाश की ओर !

बादलों की गोद में आइए

और फ़ुरसत भरे सुहाने पलों में खो जाइए!

यह एक खुला आमंत्रण है सभी पर्वतीय भ्रमण स्थलों से. अनूठी विभिन्नता. दृश्यावली में. जन जीवन में. रंगों और छटाओं में !

अगर आपने कोई एक स्थल देखा भी तो क्या देखा. क्योंकि हर एक का है अपना विशेष आकर्षण —सम्मोहन... और शांतिदायक, निश्चल वातावरण. जी हाँ! 'हिलिडे' है आराम और फ़ुरसत का नया अंदाज़!

खुशियों भरी नई राहों पर रखिए क़दम

सुबह की सैर पर निकलिए. प्रकृति के अद्‌भुत खजाने पर से पर्दा हटाते हुए सूरज को देखिए. जंगली फूल चुनिए. शीतल, साफ झरनों संग खेलिए. घुड़सवारी कीजिए. मछलियाँ पकड़िए. या पर्वतों के बीच सरसराती हवा का गूंजता संगीत सुनिए.

किसी मुस्कराहट का राज़ बन जाइए.

'हिलिडे' है आपके लिए कुछ मनचाहा करने का अवसर !

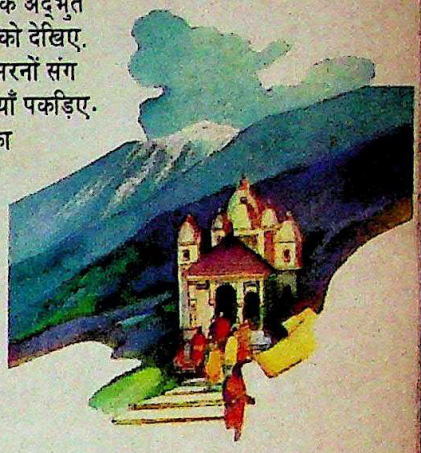

ऊंचाइयों की चुनौती स्वीकारिए

अनजाने इलाकों की पैदल सैर कीजिए. बर्फीली ढलानों पर स्कीइंग के मज़े लीजिए. अगर चाहें तो मचलती नदियों की लहरों पर बेड़ा लेकर निकल जाइए.

स्वच्छंद प्रकृति से कीजिए आमना-सामना. 'हिलिडे' पर अद्‌भुत रोमांच का अनुभव कीजिए.

जल्दी आइए!
पर्वत आपकी प्रतीक्षा में हैं!

कोई भी समय हिलिडे का सही समय

अपना 'हिलिडे' चुनिये

उत्तर
अलमोड़ा, औली, कौसानी, केदारनाथ, कुफ़री, कुल्लू, गंगोत्री, गुलमर्ग, चकराता, जोशीमठ, डाल्हौज़ी, डलहौज़ी, धनोल्टी, धर्मशाला, नैनीताल, नारकंडा, पहलगाम, बद्रीनाथ, मनाली, मसूरी, मंडी, यमुनोत्री, रानीखेत, लद्दाख, लाहौल, लेह, शिमला, स्पीती, श्रीनगर...

दक्षिण
ऊटी, कुन्नूर, कूर्ग, कोटागिरि कोडाइकनाल, पोन्मुडी, यरकाड...

पूर्व
आइज़ॉल, कलिमपोंग, कूर्सियांग, कोहिमा, गंगटोक, दार्जिलिंग, शिलांग...

पश्चिम
खंडाला, चामडी, पंचगनी, महाबलेश्वर, माउण्ट आबू, लोनावला, सपूतारा...

... और बहुत से अन्य स्थल...
आप स्वयं खोजिए.

पर्यटन मंत्रालय
भारत सरकार

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अमूल चॉकलेट
प्यार की मीठी भेंट

वितरक :
गुजरात को-ऑपरेटिव
मिल्क मार्केटिंग
फेडरेशन लिमिटेड, आणंद

5 स्वादिष्ट चॉकलेट
अमूल मिल्क चॉकलेट, अमूल क्रिस्प, अमूल कॉफ़ी,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रिपोर्ट की पहली बलि

बंबई के जे.जे. अस्पताल में मिलावटी ग्लिसरॉल के इस्तेमाल से हुई 14 मौतों की जांच कर रहे लेंटिन आयोग की रिपोर्ट विधानसभा पटल पर आने से पहले ही इसने पहली बलि ले ली. पिछले पखवाड़े स्वास्थ्यमंत्री भाई सावंत ने यह कहते हुए अपना इस्तीफा दे दिया कि आयोग ने उनकी भूमिका के बारे में "मुझे सफाई का समुचित मौका दिए बिना अन्यायपूर्ण और अनुचित टिप्पणियां की हैं और मनमाने नतीजे निकाले हैं." सावंत ने कहा, "आयोग ने बिना दस्तावेज देखे मेरे पूर्ववर्ती (डॉ. बलिराम हिरे, प्रमिला टोपले, के.एम. बापू पाटील) के दिए आदेशों को मेरे ही दिए आदेश मान लिया. मुझे कुछ अफसरों की मौखिक गवाही की बिना पर ही दोषी ठहरा दिया गया."

महेंद्र पारिख

सावंत: विरोधस्वरूप इस्तीफा

न्यायाधीश बख्तावर लेंटिन ने सावंत की टिप्पणियों पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी उन्होंने उसे ही पूरा किया है. लेंटिन ने कहा, "उन्हें अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है." जनवरी 1986 में हुई मरीजों की मौतों के बारे में यह भारी भरकम और सनसनीखेज रिपोर्ट पिछले साल 30 नवंबर को पेश की गई थी.

विपक्षी नेताओं ने सावंत के इस्तीफे का स्वागत तो किया लेकिन वे इसे बहुत देर से उठाया गया कदम मानते हैं. सावंत ने बड़ा अच्छा मौका चुना. उन्होंने विधानसभा सत्र शुरू होने से ठीक कुछ दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया. नतीजतन अब जब विधानसभा में रिपोर्ट पर चर्चा होगी तो विपक्ष के जोरदार हमले मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण को ही झेलने पड़ेंगे.

तबियत सुधारेंगे नए उद्यमी

पश्चिम बंगाल में उद्योगों के बाद अब स्वास्थ्य सेवाएं निजी क्षेत्र को सौंपी जा रही हैं. कुछ साल पहले माकपा की अगुआई वाली वामपंथी सरकार ने उद्योगपतियों को राज्य में पूंजी लगाने के लिए न्यौता दिया था. अब वाम मोर्चा सरकार राज्य के कुछ सरकारी अस्पतालों का जिम्मा निजी उद्यमियों को सौंपना चाहती है. अस्पताल चलाने के लिए निजी उद्यमियों को आमंत्रित करने का मतलब यह है कि प्रशासन ने स्वास्थ्य सेवाएं देने में अपनी अक्षमता कबूल कर ली है. पिछले साल अप्रैल में ही स्वास्थ्यमंत्री बने प्रशांत सूर ने कहा, "मैं इसके अलावा क्या कर सकता हूं? अस्पतालों के अधीक्षकों और मेडिकल ऑफिसरों में प्रशासनिक क्षमता ही नहीं है. वे गलतियां करने वाले डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने से डरते हैं." सरकार इस प्रस्ताव को अमली जामा पहना सकेगी या नहीं इस बारे में अभी भी संदेह व्यक्त किए जा रहे हैं. यदि यह सरकारी योजना मूर्त रूप ले भी लेती है तब भी अभी कुछ समय तक तो लोगों को सरकारी अस्पतालों के भरोसे ही रहना पड़ेगा.

मेडिकल कॉलेज के दौरे पर सूर

अशोक बोस

सनसनीखेज फैसला

संसद में शून्यकाल के दौरान 33 वर्षीय चिंतामोहन की 'दुखी मन से' इस्तीफा देने की घोषणा सुनकर सदन में बैठे सत्ताधारी और विपक्षी दलों के सदस्य अवाक रह गए. चिंतामोहन ने अपने दल तेलुगु देशम और संसद दोनों से ही इस्तीफा दे दिया. उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नंदमूरि तारक रामराव पर स्वैच्छाचारी शासन चलाने, अपने परिवार का हित साधने और हरिजनों तथा पिछड़े वर्गों के हितों की अवहेलना करने का आरोप लगाया.

बाबजी/ जनता स्टूडियो

चिंतामोहन: प्रबल महत्वाकांक्षाएं

उनका इस्तीफा अपनेआप में अनोखा है क्योंकि सांसद या विधायक अपने विशेषाधिकारों को छोड़ना नहीं चाहते और आम तौर पर एक दल से पाला बदलकर दूसरे दल में पहुंच जाते हैं. चिंतामोहन ने कहा, "कई दलों के सांसदों ने मुझसे अपने फैसले पर दुबारा गौर करने को कहा."

लेकिन चिंतामोहन के दिमाग में एक दूसरी योजना है. वे हरिजन हैं और पिछले अगस्त में उन्होंने संसद में यह कहकर सनसनी फैला दी थी कि हरिजनों को अलग राज्य दिया जाए और सुरक्षा के लिए हथियार भी. अब वे अगले आम चुनाव की तैयारी के लिए हरिजनों को एक नई दलित पार्टी के तहत संगठित करेंगे.

लापरवाही का नतीजा

बंगलूर से 60 किलोमीटर दूर चिंतामणि गांव में मामला होम करते हाथ जलने का है. नेत्र शिविर में आंख का ऑपरेशन करवाने गए 151 गरीबों में से 64 की आंखों की रोशनी ऑपरेशन के बाद गई. बीस व्यक्ति तो एकदम अंधे हो गए क्योंकि उनकी एक ही आंख ठीक थी. 8 मार्च को इस हादसे को जगजाहिर किया एक स्वयंसेवी संस्था के प्रधान जी.के.सी. रेड्डी ने.

ऐसा नहीं कि नेत्र शिविर के आयोजक अनुभवी नहीं थे. एच.एन. थिम्मा रेड्डी के नेतृत्व वाले डॉक्टरों ने इस दल ने 1981 से अब तक कर्नाटक में 273 ऐसे शिविर आयोजित किए हैं और 28,000 लोगों की आंखों के ऑपरेशन किए हैं.

लेकिन आयोजक ऑपरेशन के बाद मरीजों की सही देखभाल और संभवत: ऑपरेशन के यंत्रों को सही तरीके से जीवाणुमुक्त न करने के तो दोषी हैं ही. यह शिविर 28-29 जनवरी को लगा था. और चूंकि उसी जगह एक शादी होनी थी इसलिए शिविर जल्दबाजी में समेट लिया गया.

शुरू में राज्य सरकार ने इस मामले पर ध्यान नहीं दिया. लेकिन जब आलोचना के स्वर मुखर हो उठे तो सरकार ने हैदराबाद के प्रतिष्ठित नेत्र सर्जन डॉ. शिव रेड्डी के नेतृत्व में एक सदस्यीय जांच समिति नियुक्त कर दी.

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"राजीव के सलाहकारों का दूर-दूर तक कोई लेना

मानो वे एक मदमस्त योद्धा हों. इन दिनों कहा तो यही जा रहा है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह हारने वाले नहीं. उनका पहले वाला आत्मसंशय और आत्मविश्लेषी रुख अब नहीं रहा. उनके चेहरे से दूसरे नेताओं की तरह ही आत्मविश्वास और निश्चिंतता टपकती है.

पिछले पखवाड़े यह साफ हो गया कि वे विपक्ष की एकता वार्ताओं के केंद्रबिंदु बन गए हैं. रामकृष्ण हेगड़े, देवीलाल और चंद्रशेखर के फोन उनके घर लगातार आते रहे. उनके सामने वाले बरामदे में सभी विपक्षी पार्टियों के लोगों की भीड़ जुटी रही. उन्होंने एक आगंतुक से कहा, "अगले हफ्ते मेरे साथ इलाहाबाद चलिए. मैं अमिताभ बच्चन को वहां से चुनाव लड़ने की चुनौती देता हूं."

बार-बार आते फोन और आगंतुकों से सलाह-मशविरे के बीच वी.पी. सिंह ने वरिष्ठ संपादक ***प्रभु चावला*** *और फीचर संपादक* ***इंद्रजीत बधवार*** *से लंबी बातचीत की. नाजुक मुद्दों पर वे पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़-चढ़कर बोले. इनमें अपने वित्तमंत्रित्व काल के दौरान राजीव गांधी के साथ उनके रिश्तों से लेकर एचडीडब्ल्यू और एचबीजे पाइपलाइन सौदों तक मुद्दे शामिल थे. बातचीत के कुछ अंश:*

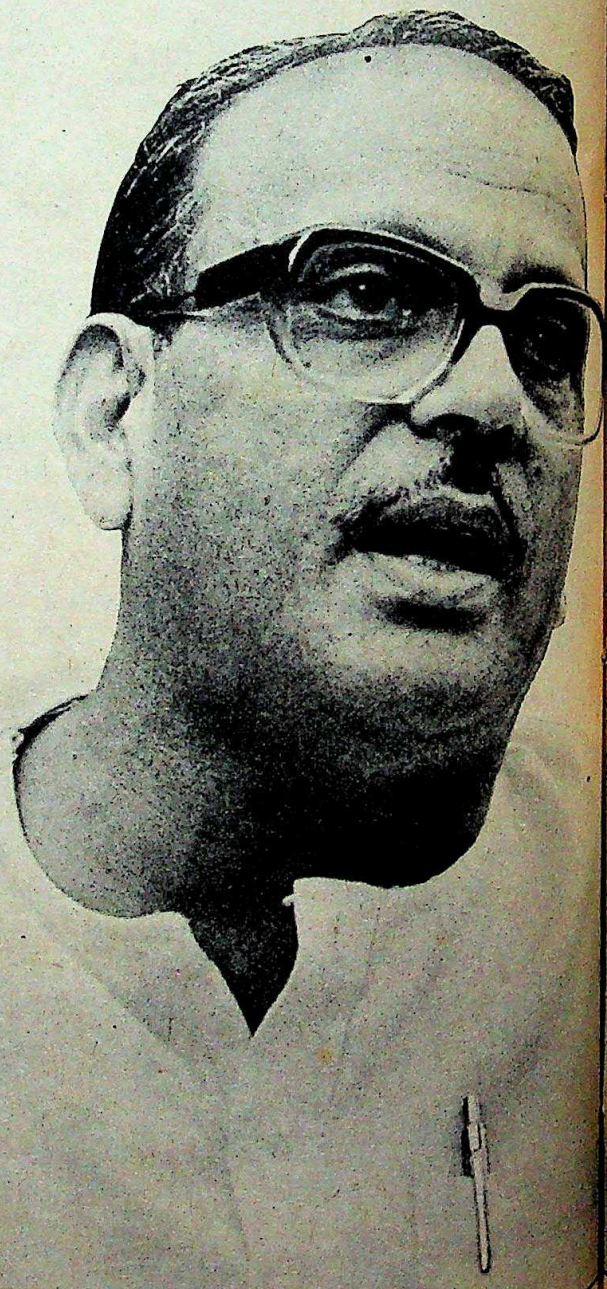

• *राजीव गांधी पर आपका क्या आरोप है?*

राजीव हर मोर्चे पर बुरी तरह नाकाम रहे हैं. न तो उनमें दिशा ज्ञान है और न ही देश के प्रति समर्पण की भावना. उन्होंने आंध्र प्रदेश सरीखी कुछ राज्य सरकारों को राष्ट्रविरोधी बताकर और उन्हें बर्खास्त करने की धमकी देकर लोकतंत्र के मूल आधार को ही चुनौती दी है. आखिर इन सरकारों को भी तो लोगों ने ही चुना है. न्यायपालिका, जो कार्यपालिका को

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रों का राजनीति से ना देना नहीं है''

नियंत्रण में रखने का एक ताकतवर हथियार है, का भी पक्षपाती उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग किया गया. न्यायाधीशों को राजनैतिक उद्देश्यों की खातिर इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री ने न्यायपालिका की गरिमा को गहरी ठेस पहुंचाई. एक आयोग भजनलाल को निर्दोष ठहराता है तो दूसरा भूरेलाल और विनोद पांडे सरीखे ईमानदार अफसरों को सजाएं देता है. ठक्कर-नटराजन आयोग की रिपोर्ट को संसद में रखकर जहां सरकार तुरंत हरकत में आती है, वहीं दिल्ली दंगों पर मिश्र आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल देती है.

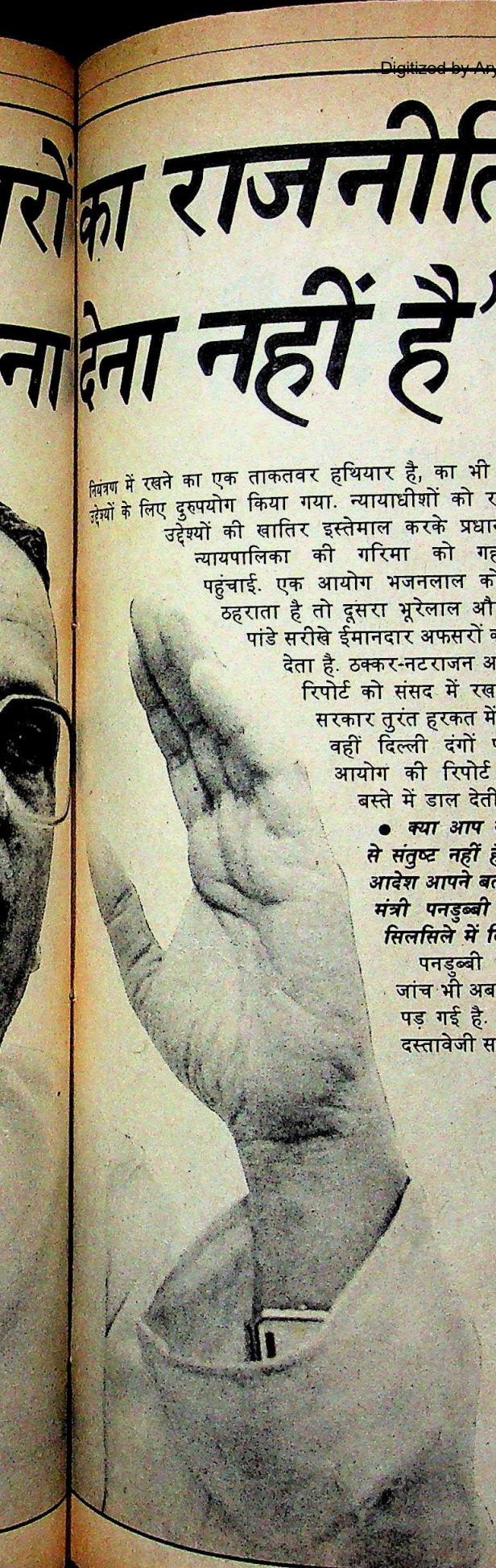

● *क्या आप उस जांच से संतुष्ट नहीं हैं जिसका आदेश आपने बतौर रक्षा-मंत्री पनडुब्बी सौदे के सिलसिले में दिया था?*

पनडुब्बी सौदे की जांच भी अब खटाई में पड़ गई है. इसके तो दस्तावेजी सबूत हैं कि एचडीडब्ल्यू से किए इकरारनामे में मौजूदा खरीद पर ही नहीं बल्कि भविष्य की खरीद पर भी दलाली देने की बात दर्ज है. जब रक्षा सचिव ने मुझे फाइलों में दर्ज एजेंट का नाम बताया तो मैंने जांच की सिफारिश की थी. और अपनी टिप्पणी में भी मैंने उस एजेंट का नाम लिखा था जिसे सात फीसदी दलाली मिलनी थी. दिसंबर में मैंने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी कि उन्हें इकरारनामे पर कोई कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि कंपनी ने डिजाइन दक्षिण अफ्रीका को दे दिए हैं. पर राजीव गांधी टस से मस नहीं हुए. आखिर जब पश्चिम जर्मनी के अधिकारियों ने यह बात कबूल कर ली तो उन्हें आदेश स्थगित करने पड़े. राजीव देश की सुरक्षा के प्रति इतने गंभीर हैं.

● *प्रधानमंत्री के साथ आपके संबंध कब बिगड़ने शुरू हुए?*

जब मैं वित्तमंत्री बना तो यही मानता रहा था कि राजीव अपनी मां से बेहतर नेता हैं. मुझे लगता था कि वे पूर्वाग्रहों से मुक्त और अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों पर भरोसा रखने वाले व्यक्ति हैं. हम दोनों की एक-दूसरे से खूब पटती थी. मंत्रालय में मुझे पूरी स्वतंत्रता थी. इसी एहसास की वजह से कई बार तो मैं 20 घंटे रोज काम करता. पर धीरे-धीरे मुझे प्रधानमंत्री में परिवर्तन नजर आने लगा. वे अब किसी पर विश्वास नहीं करते बल्कि खुद या अपने दफ्तर के जरिये निर्देश देने लगे थे. मुझे एहसास होने लगा कि कोई दूसरी ताकतें प्रधानमंत्री को इस्तेमाल कर रही हैं. एचबीजे पाइपलाइन वाले मामले पर फैसला लेते समय तो यह बात बिलकुल साफ हो गई. इससे पहले अनेक समितियों और विशेषज्ञ दलों ने निविदाओं की जांच में पाया था कि दूसरों के मुकाबले स्नैम प्रोगेती की निविदा 70 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है. पर प्रधानमंत्री को वित्त मंत्रालय पर भरोसा नहीं हुआ. उन्होंने मुझे निविदा की फिर से जांच कराकर यह देखने को कहा कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया और दूसरे विशेषज्ञ दलों ने उसका ठीक मूल्यांकन किया है या नहीं. मैंने वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त कर दी. उसने भी निविदा को ज्यादा खर्चीला पाया. फिर प्रधानमंत्री ने मुझे कुछ निर्देश लिखकर भेजे और उनके आधार पर स्नैम प्रोगेती की निविदा का मूल्यांकन करने को कहा. हैरानी की बात है कि प्रधानमंत्री के भेजे निर्देशों में वैसी ही बातें थीं जैसी स्नैम प्रोगेती के एजेंट आक्टोवियो क्वात्रोची ने इससे पहले वित्त मंत्रालय को सुझाई थीं. मैंने फाइल पर लिख दिया कि पिछले 15 साल से चले आ रहे मानकों के आधार पर स्नैम प्रोगेती को यह ठेका नहीं दिया जा सकता. आखिर यह ठेका स्नैम प्रोगेती को नहीं मिल पाया. पर इटालियन कंपनी को समर्थन न देने की कीमत हर किसी को चुकानी पड़ी. नवल किशोर शर्मा बाहर कर दिए गए. एक समय इस काम को देख रहे कैबिनेट सचिव कौल को वाशिंगटन भेज दिया गया. गैस अथॉरिटी के चीमा को भी चलता कर दिया गया और आखिर मुझे भी दूसरे मंत्रालय में पटक दिया गया.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"अजिताभ का नाम आते ही अफसरों की डर से घिग्घी बंध

● ***क्या ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको वित्त मंत्रालय से निकालने की मुहिम चलाई?***

अपने मंत्रियों को चुनना प्रधानमंत्री का अधिकार है. पर किसी को टीम में शामिल करने या उसे निकालने में उन्हें बाहरी दबाव का शिकार नहीं होना चाहिए. मुझे तो यह भी पता चला कि मंत्रियों की तुलना में प्रधानमंत्री के कुछ उद्योगपति मित्रों की उन तक पहुंच ज्यादा आसान है. वे जब भी चाहते प्रधानमंत्री कार्यालय में आ धमकते. लगता है कि विभिन्न मुद्दों पर मेरी निष्पक्ष राय से प्रधानमंत्री खुश नहीं थे. मसलन वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर हासिल करने पर मतभेद पैदा हुए. शुरू की एक बैठक में मैंने प्रधानमंत्री को बताया था कि यह परियोजना आर्थिक तौर पर सफल नहीं रहेगी. मैंने मजाक में कहा भी कि उन्हें उड़ाने के बजाय खरीदकर हैंगरों में रख देना आर्थिक दृष्टि से फायदेमंद रहेगा. ताज्जुब है कि प्रधानमंत्री ने अचानक इस सौदे का विरोध छोड़कर हेलीकॉप्टर हासिल करने के आदेश दे दिए. अब वे फालतू पड़े हुए हैं.

● ***क्या आपका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री पर मंत्रिमंडल के सहयोगियों से ज्यादा उनके उद्योगपति दोस्तों का असर है?***

मुझे यह नहीं मालूम पर एक बात तय है कि उन्हें कुछ ऐसे लोग सलाह देते हैं जिनका न तो राजनीति से और न ही कांग्रेस पार्टी से कुछ लेना-देना है. एक बार तो मुझे यह तक लगने लगा था कि कुछ लोग प्रधानमंत्री सचिवालय में बैठे-बैठे ही वित्त मंत्रालय की गाड़ी हांकना चाहते हैं. विभिन्न व्यापारिक सौदों के सिलसिले में प्रधानमंत्री या दूसरे अधिकारी अक्सर मुझे बुलावा भेज देते थे. राजस्थान में विदेशी सहयोग से लगने वाले बिड़ला के उर्वरक संयंत्र को हरी झंडी दिखाने के लिए मुझ पर जबरदस्त दबाव डाला गया. जब परियोजना वित्त मंत्रालय में आई तो हमें पता चला कि यह 70 से 100 करोड़ रुपए तक महंगी है. सप्लायर कंपनी ने वही संयंत्र दूसरे देश को सस्ते दामों पर बेचा था. प्रधानमंत्री ने मुझे बुलाया और मुझसे पूछा कि बिड़ला की योजना को मंजूरी क्यों नहीं दी गई. उन्होंने मुझसे कहा 'विश्वनाथ, मुझे लगता है कि वित्त मंत्रालय में कोई लॉबी इस परियोजना के खिलाफ काम कर रही है.' परियोजना के लिए 24 करोड़ रुपए की नकद सबसिडी देने का भी प्रस्ताव था. मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे यह रकम बिड़ला को तोहफे के तौर पर दी जा रही हो. मैंने फाइल प्रधानमंत्री को भेज दी और उस पर लिख दिया कि बिड़ला को इजाजत तभी दी जा सकती है जब वे विश्वव्यापी टेंडर जारी करें.

रक्षा सचिव ने मुझे फाइलों में दर्ज एचडीडब्ल्यू दलाल का नाम बताया था. मैंने उसका नाम लिखते हुए जांच की सिफारिश की, जिसे सात फीसदी दलाली मिलनी थी. लेकिन एक साल में कुछ भी नहीं हुआ

● ***लेकिन आम तौर पर माना जाता है कि प्रधानमंत्री खुलेपन से बर्ताव करते हैं और मंत्रिमंडल के सहयोगियों को विश्वास में लेते हैं.***

प्रधानमंत्री संबंधित मंत्री से सलाह लिए बगैर ही फैसला कर लेते हैं. उन्होंने वित्त मंत्रालय को विश्वास में लिए बिना ही नई शिक्षा व कपड़ा नीति की घोषणा का फैसला कर लिया था. नई शिक्षा नीति सदन के पटल पर रखे जाने से पहले मैं उनके पास गया और उनसे कहा कि हमें इसके आर्थिक पहलुओं की पड़ताल कर लेनी चाहिए पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया. अब हम देख रहे हैं कि इसके अमल के लिए हमारे पास पैसा ही नहीं है.

● ***बच्चन बंधुओं की क्या भूमिका थी?***

बच्चन बंधुओं को लेकर जिस किसी ने सवाल उठाया उसे या तो निकाल दिया गया या परेशान किया गया. मैंने जब प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि वे स्विट्जरलैंड में अजिताभ के घर खरीदने के मामले पर जांच बिठाएं तो मुझे 20 घंटे के अंदर ही पार्टी से बाहर कर दिया गया. 'इंडियन एक्सप्रेस' ने बच्चन के खिलाफ सबूत पेश किए तो उस पर छापा मारा गया. भूरेलाल और विनोद पांडे ने उनके (बच्चन बंधुओं के) संदेहास्पद सौदे की सचाई जानने की कोशिश की तो उन्हें

नामस भोजानी

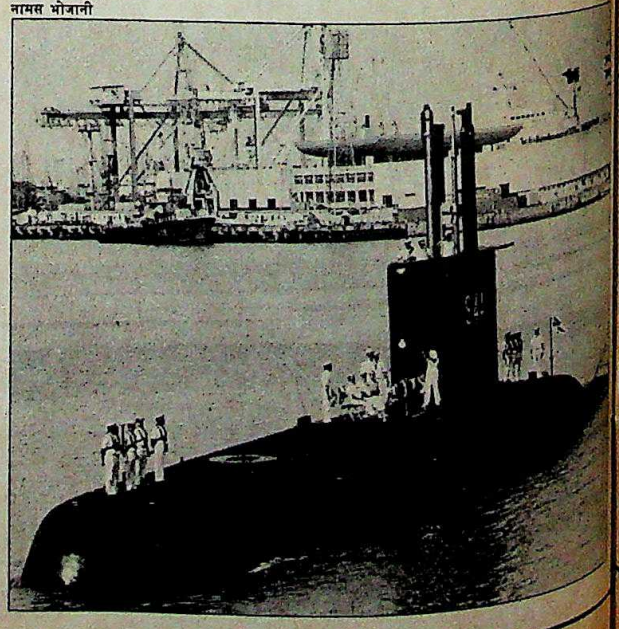

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ही वित्त मंत्रालय के बंध जाती थी''

अनुशासनात्मक कार्रवाई की धमकी दी गई.

• *जब आप वित्त मंत्रालय में थे तब क्या आपने बच्चन बंधुओं के खिलाफ जांच या उन पर छापा डालने का कोई आदेश दिया था?*

अपने इस्तीफे के दो हफ्ते बाद जब मैं प्रधानमंत्री से मिला तो उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें पता लगा है कि भूरेलाल बच्चन बंधुओं के आर्थिक मामलों की पड़ताल कर रहे हैं. वित्त मंत्रालय तब राजीव के पास था. मुझे लगा कि वे इससे खुश नहीं हैं.

• *क्या प्रधानमंत्री बच्चन बंधुओं को बचा रहे थे?*

अगर देश का प्रधानमंत्री अपनी निजी छुट्टियां एक ऐसे आदमी के साथ बिताता है जिस पर आर्थिक अपराधों के कई आरोप हैं तो जांच करने वाला इसका क्या मतलब लगाएगा? यह बहुत साफ है कि जिस किसी ने शक्तिमान बच्चन बंधुओं को छूने की कोशिश की वह संकट में पड़ गया. एक फिल्मी हीरो और उसके भाई को बचाने के लिए सरकार ने सभी कानून-कायदों को ताक पर रख दिया. जिन लोगों के खिलाफ छोटे-मोटे मामले थे उन सभी के यहां छापे मारे गए, उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए पर अजिताभ के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. जैसे अजिताभ उस तोते की तरह हों जिसमें राजा के प्राण बसते हैं और हर कोई उस तोते की प्राण रक्षा में जुटा है. अजिताभ का नाम आते ही अधिकारियों की घिग्घी बंध जाती थी.

• *छापों के प्रति तो आप बहुत दृढ़ थे. पर आपने ललित मोहन थापर के मामले में समझौता क्यों कर लिया?*

उसमें कोई समझौता नहीं हुआ. उन्होंने गलती मान ली और पैसा वापस लाने का वायदा किया. एक कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अफसर मेरे सामने हमेशा थापर की तरफदारी करते थे. प्रधानमंत्री ने भी यही किया.

• *उद्योगपतियों पर छापों के दौरान क्या आपको राजीव का समर्थन हासिल था?*

कई मिले-जुले संकेत थे. वे कभी एक बात कहते, कभी दूसरी. पर उनके साथ मेरी कार्यशैली उतनी ही दृढ़ थी जितनी श्रीमती गांधी के साथ. मैंने अपना कार्यक्षेत्र और अपनी जिम्मेदारियां तय कर रखी थीं. मैंने साफ कह रखा था कि मैं रोज प्रधानमंत्री के पास हाजिरी देने नहीं जाऊंगा. मैंने उन्हें बता दिया था कि मैं आपका दोस्त नहीं बल्कि मंत्री हूं.

• *इन छापों में आपकी भी कोई सीधी भूमिका थी?*

देखिए, मैंने उद्योगपतियों से साफ कह दिया था कि निर्णय का अधिकार मेरे पास है. मैं आर्थिक गतिविधि और उत्पादन की बाधाओं को दूर करके आप लोगों की राह आसान करूंगा. पर हर खेल की अपनी सीमाएं होती हैं. अगर आप हद से बाहर गए या गलत काम किया तो मैं आपको बख्शूंगा नहीं.

• *ऐसा लगा मानो आपने कुछ उद्योगपतियों की तरफदारी की हो.*

नहीं. ओरके उद्योग का मामला ही लें. हमने कपिल मेहरा को गिरफ्तार करके फौजदारी मुकदमा दायर किया. मगर जब डिबेंचर का मामला आया तो मेरे अफसरों ने उसकी मंजूरी न देने की सलाह दी. लेकिन मैंने मंजूरी दे दी. कुर्सी पर बैठकर आप निजी इच्छाएं नहीं चला सकते.

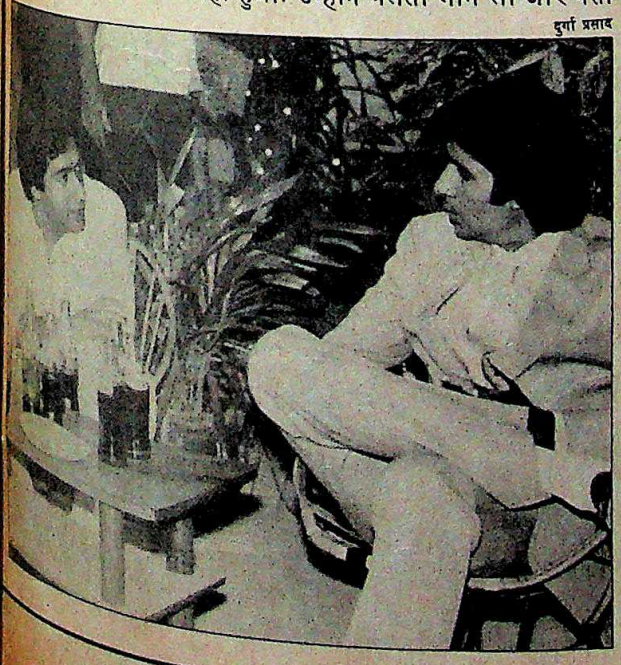

दुर्गा प्रसाद

मैं प्रधानमंत्री से मिला तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या भूरेलाल बच्चन बंधुओं के आर्थिक मामलों की जांच कर रहे हैं. मुझे लगा कि वे खुश नहीं हैं. जब मैं वित्तमंत्री था तब अजिताभ का नाम आते ही अधिकारियों की घिग्घी बंध जाती

• *रिलायंस के विरोध में आप बांबे डाइंग से सहयोग करते रहे?*

बेहतर जानकारी देने वाले तो प्रतिद्वंद्वी और असंतुष्ट लोग, बर्खास्त कर्मचारी या ठुकराई गई रखैलें ही होती हैं. गुप्तचरी के इन परंपरागत सूत्रों को कैसे दरकिनार किया जा सकता है?

• *रक्षा सौदों की जांच की मांग करने के बाद लगे आघातों से क्या आप उबर चुके हैं?*

सचमुच, दोस्तों की मदद के बिना मैं शायद ही उबर पाता. मुझे उनसे प्रेरणा मिली. उन्होंने मुझे साहस दिया और उस स्तर पर ला खड़ा किया जहां मैं सरकार में बने रहकर कभी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"इस्तीफा देने के बाद भी मुझ और मंत्रालय चुन लेने की पेश

नहीं पहुंच पाता.

● ***जब आप मंत्री थे तो अपनी पार्टी के लोगों की ओर से आप पर हुए हमलों को रोकने के लिए आपने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया?***

मैंने उन्हें बताया कि ये हमले नाजायज और गलत हैं. मुझे जो चाहे गाली दे लीजिए पर मेरी देशभक्ति पर उंगली मत उठाइए. उन्होंने मुझसे कहा कि समूची पार्टी मेरे खिलाफ उठ खड़ी हुई है और इसलिए स्थिति संभालने में कुछ वक्त लगेगा.

● ***क्या आपने यकीन कर लिया?***

इतना ही कह सकता हूं कि कभी मैं भी उसी राजनैतिक मशीन का पुर्जा हुआ करता था और मुझे पता है कि ये हमले कितने सुनियोजित होते हैं. कई कहानियां तो सीधे माखनलाल फोतेदार के दफ्तर से प्रसारित हो रही थीं. मैं ऐसे तरीके भलीभांति जानता हूं. मुझे ठीक पता था कि परदे के पीछे से कौन हमले आयोजित कर रहा है. पर मैं फंसने वाला नहीं था. मैंने राजीव से कह दिया कि पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाने में वे नाकाम सिद्ध हो रहे हैं.

● ***क्या उन्होंने कोई कार्रवाई की?***

पता नहीं. मगर एक बार किसी के हवाले से उन्होंने मुझे बताया कि मैंने चिकमगलूर चुनाव के दौरान श्रीमती गांधी का प्रचार नहीं किया था. मैंने कहा कि इसमें किसी और से पूछने की क्या जरूरत पड़ी थी, मुझसे ही पूछ लेते. आखिर मैं आपका साथी हूं.

● ***पर इतने अरसे बाद गड़े मुर्दे उखाड़ना शोभा नहीं देता.***

मुझ पर आजमगढ़ के चुनाव में मोहसिना किदवई का प्रचार न करने का भी आरोप था. मैं तो हक्का-बक्का रह गया क्योंकि मैंने पूरा एक हफ्ता वहां लगाया था. मैंने इस बात की तसदीक के लिए राजीव से तुरंत मोहसिना को बुलाने को कहा. राजीव ने उनका नंबर मिलाकर फोन पर उनसे कुछ पूछा और मुझे बताया कि उन्होंने इसकी तसदीक की है. मैंने फोन लेकर सीधे मोहसिना से बात की और उनसे पूछा कि मैं पूरा एक हफ्ता वहां रहा था, क्या आपको याद नहीं? वे कुछ बड़बड़ाईं कि शायद उन्हें समय का ध्यान नहीं है.

● ***फिर आपने क्या किया?***

शायद उसी समय मुझे एहसास हुआ कि अब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं. संगठन में न तो कोई मेरी इज्जत है और न भविष्य. आखिर 1977, 1978 और 1979 में मैं श्रीमती गांधी की खातिर जेल गया था और ये लोग उनके प्रति मेरी वफादारी पर ही उंगली उठा रहे थे. हालत यह हो गई कि पार्टी के प्रति वफादारी साबित करने के लिए मुझे जेल के प्रमाणपत्र लेने पड़े.

● ***क्या यह सही है कि रक्षामंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद और यहां तक कि हरिद्वार रैली तक भी आपसे संपर्क किया जाता रहा?***

राजीव के साथ सीधे कोई भेंट नहीं हुई. मगर बिचौलियों ने कई बार मुझसे संपर्क करके अनेक पेशकशें कीं.

● ***क्या उन्होंने वित्त मंत्रालय लौटाने की भी पेशकश की?***

इसके अलावा कोई भी बड़ा मंत्रालय.

● ***और आपने मना कर दिया?***

बच्चन बंधुओं के बारे में मेरे चिट्ठी लिखने के बाद भी पेशकशें की जाती रहीं पर यह मेरा अपमान ही था. डर और लालच विश्वास की जगह तो ले नहीं सकते. क्या राजीव को मेरे बारे में जानकारी नहीं? पार्टी से निष्कासित किए जाने की पूर्व संध्या पर ही राजीव के एक दूत ने मुझे प्रधानमंत्री से मुलाकात का न्यौता दिया. मैंने कह दिया कि पहले मैं इस मुलाकात का मकसद और उसमें विचारणीय मुद्दों के बारे में जानना चाहूंगा. अगले दिन मुझे निष्कासित कर दिया गया.

● ***वाम बनाम दक्षिणपंथ के सवाल पर आपकी राय?***

मेरा हमेशा से मत रहा है कि मध्यमार्गी पार्टियों को एक हो जाना चाहिए. यह प्रक्रिया अभी चल रही है. इसके बाद उन्हें क्षेत्रीय पार्टियों

प्रधानमंत्री ने मुझे कुछ निर्देश लिख भेजे और एचबीजे पाइपलाइन के लिए स्नैम प्रोगेती की निविदा का मूल्यांकन करने को कहा. प्रधानमंत्री ने वही मुद्दे गिनाए जो स्नैम के एजेंट आक्टोवियो क्वात्रोची ने वित्त मंत्रालय को भेजे थे

भवान सिंह

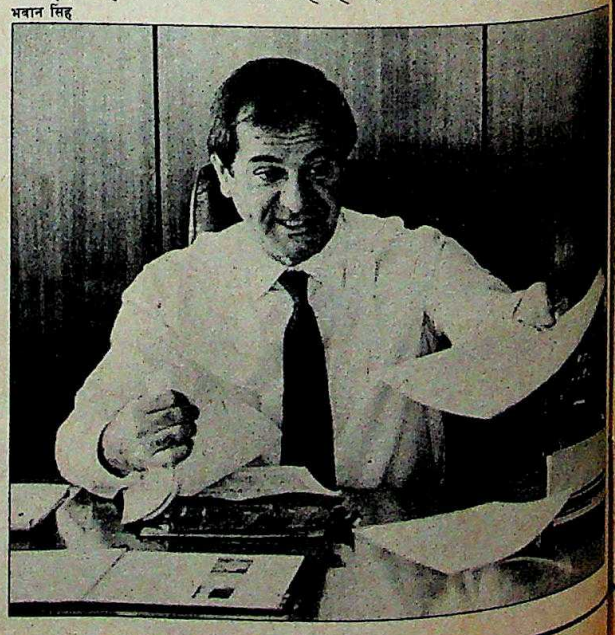

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मुझे वित्त के अलावा कोई पेशकश की गई थी''

से गठजोड़ बनाने चाहिए. और अंत में उन्हें वामपंथी पार्टियों और भाजपा से सीटों का वास्तविक तालमेल करना चाहिए. जनमोर्चा एक ऐसा मंच रहेगा जिसके सदस्य किसी भी पार्टी से खड़े हो सकते हैं.

• यह बात आपने पहले क्यों नहीं स्पष्ट की? इस पर तो बहुत उत्साह दिखाई देता था.

मैं क्यों करता? मुझे लोगों को साथ लेकर चलना था. क्या कोई सर्जन ऑपरेशन करते समय सर्जरी पर लेक्चर देगा? मुझे पता है आपका अगला फंदेदार सवाल यह होगा कि भाजपा और वामपंथी पार्टियों में से 'आप' किसे चुनेंगे और आप चाहेंगे कि मैं जवाब दूं–वामपंथी पार्टियां. पर मुझसे यह कोई नहीं पूछता कि राजीव और भाजपा में से आप किसे पसंद करेंगे?

• पर इस बात की क्या गारंटी कि विपक्ष केंद्र और राज्यों में स्थायी सरकार बना सकेगा?

कांग्रेस शासित राज्यों में भी स्थिरता कहां है. बीच कार्यकाल में जहां कोई भी गैर-इंका मुख्यमंत्री नहीं बदला गया, वहीं राजीव ने अपने एक दर्जन मुख्यमंत्रियों को मक्खी की तरह निकाल दिया जो मुश्किल अपना आधा कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए थे. कांग्रेस वाले राज्यों में तो कहीं ज्यादा अस्थिरता है. अब राजमहल से फरमान जारी होता है और बूटा सिंह जैसे दरबारी उसे बजा लाते हैं.

• ज्ञानी जैल सिंह की उस टिप्पणी पर आप क्या कहेंगे जो उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में पैसे की भूमिका पर की है?

जैल सिंह ने अपने बयान की सफाई में कहा है कि अगर वे दुबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते तो कुछ लोग उसके लिए पैसा खर्च करने को तैयार थे. पर उस समय भी मेरा यही विचार था और अब भी यही है कि कोई गैर-निर्वाचित संस्था चुने गए प्रधानमंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकती. ऐसा होता तो देश से लोकतंत्र की अर्थी उठ जाती.

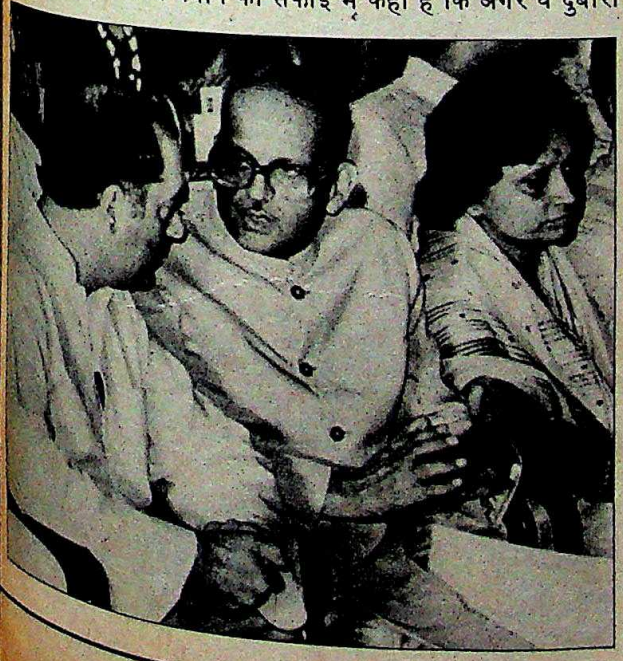

मैं ने साफ कह दिया था कि मैं रोज प्रधानमंत्री के पास हाजिरी देकर दरबारगीरी नहीं करूंगा. मैंने उन्हें बता दिया कि मैं आपका दोस्त नहीं, मंत्री हूं. मैंने अपनी जिम्मेवारियां तय कर रखी थीं

• क्या आप प्रधानमंत्री बनना मंजूर करेंगे?

एक अरसे बाद मैंने आजादी हासिल की है. लगता है 'मैं' और पद दोनों एक साथ नहीं चल पाते.

• तो आप महात्मा गांधी बनना चाहते हैं?

हर आदमी अपनी तरह का होता है. पर यह मत भूलिए कि मैं भी विकल्प की तलाश में हूं.

• तो आप अभी अकेले ही हैं?

मैं अकेला ही चला हूं और इस्तीफा देते समय भी अकेला ही था.

• पर जब जनता चाह रही है, आप उसकी सामूहिक भावना को नजरअंदाज कर रहे हैं. यह तो तानाशाहों वाला व्यवहार हुआ.

अगर वे स्थिर सरकार चाहते हैं तो हम उन्हें स्थिर सरकार देंगे.

• ठीक है, शुरू में तो जनता सरकार भी स्थिर ही थी पर उसका हश्र देखिए कि क्या हुआ.

पर उसने भी नेता तो पैदा किए.

• आप बार-बार मैदान छोड़ते क्यों दिखते हैं? क्या आप डरते हैं?

मैं वही करता हूं जो मेरे भीतर की शक्ति मुझसे कराती है, मुझे कोई डर नहीं.

• आपने उत्तर प्रदेश से पीछा छुड़ाया. फिर वित्त मंत्रालय से भी भाग निकले.

पर मैं भाग नहीं रहा. मैं हमला भी बोल रहा हूं. मंत्रिपद मुझे रास नहीं आता. यह वैसी ही बात हुई कि तीन बार तलाक ले चुकने के बाद मैं एक और शादी क्यों कराऊं. मैं उत्तर प्रदेश से नहीं भागा. मैं कुर्सी छोड़ना चाहता था ताकि डकैती पर बहस से बच सकूं जो आंकड़ों का खेल बन गई थी.

• पर क्या यह खतरा नहीं कि आपका भी वही हश्र हो जो कभी बहुगुणा या प्रणब मुकर्जी का हुआ था?

मेरा जमीर कहे तो मैं हटने को तैयार हूं. मैंने अकेले ही इस्तीफा दिया और मुझमें अकेले चलने की ताकत है.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वी.पी. सिंह

पेचीदा व्यक्ति

प्रकाश लुप्त होने के विरोध में उबल पड़ो, उबल पड़ो.
उस शुभ रात्रि में सौम्य और शांत न बने रहो

—डाइलान थॉमस

विश्वनाथ प्रताप सिंह के बहुतेरे चाहने वालों, समर्थकों और शुभचिंतकों में एक खास किस्म का गुस्सा घुमड़ रहा है. उन्हें लगता है कि उन्होंने उनकी हेठी करा दी है. राजनैतिक राक्षस से कड़ा मुकाबला किए बगैर उन्होंने उसे छुट्टा छोड़ दिया है; वे कमजोर पड़ गए; उनकी गाड़ी छूट गई; वे पस्त हो गए, चुक गए. राजा सम्राट नहीं बन पाए.

आम तौर पर मान्यता है कि इंका से निकाले जाने के दो सौ दिन बाद भी विश्वनाथ प्रताप सिंह करना क्या चाहते हैं, यह तय ही नहीं कर पाए हैं, न तो वे व्यवस्था को चुनौती दे पाए हैं और न ही राजीव के विकल्प के रूप में उभर सके हैं. राजनैतिक गढ़ों को विध्वंस करने वाला योद्धा बाजी छोड़ गया है. उनका नाम और उनके भाषण कभी-कभार ही अखबारों में छपते हैं. और हाल के एक अखिल भारतीय जनमत सर्वेक्षण से पता चलता है कि पिछले छह महीनों में राजीव गांधी के मुकाबले उनकी लोकप्रियता 34 से घटकर 23 प्रतिशत पर आ टिकी है. यानी उसमें 11 प्रतिशत की कमी आ गई है.

सियासी पंडितों का कहना है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है. लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह के मामले में यह असंभव की साधना लगती है. अभी उनके साथ के लोग एक निर्गुण और अपने नेता के शब्दों में 'एक गैर-राजनैतिक आंदोलन' के जरिये राजनैतिक सत्ता पाने की कोशिश कर रहे हैं. इसी वजह से चारों तरफ एक ही सवाल उठ रहा है कि क्या विश्वनाथ प्रताप सिंह अप्रासंगिक हो गए हैं? इस सवाल का जवाब तो शायद अगले आम चुनाव के करीब आने पर ही मिल सकेगा. लेकिन लोगों के बीच अब निरंतर ये सवाल उठ रहे हैं: विश्वनाथ प्रताप सिंह कौन हैं? वाकई वे चाहते क्या हैं और उनका मकसद क्या है? लगभग लगातार जनता के बीच रहने के बावजूद यह व्यक्ति अपने समर्थकों, विपक्षी दलों और शायद अपनेआप के लिए भी एक पहेली बना हुआ है.

चेहरे पर सौम्यता और विचारमग्नता के भाव, सरकारी बाबुओं सी पतली मूंछें, पूरबी बोली वाला शिकायती स्वर, कभी-कभार स्त्रैण भंगिमा और घायलों से विरोधी तेवर रखने वाला यह व्यक्ति एक अबूझ पहेली बना हुआ है

चेहरे पर सौम्यता और विचारमग्नता के भाव; निचले तबके के किरानियों जैसी पतली मूंछे, पूरबी बोली की झलक वाला शिकायती स्वर; कभी-कभार स्त्रैण भंगिमा और घायल व्यक्ति की तरह विरोधी तेवर रखने वाला यह व्यक्ति अपने कट्टर समर्थकों के लिए अब भी एक अबूझ पहेली है. खुद को विश्वनाथ प्रताप के खेमे का मानने वाले हिमाचल प्रदेश के एक निष्कासित इंका विधायक विजय सिंह मनकोटिया कहते हैं, "उन्हें अब साफ-साफ कोई एक दिशा पकड़नी चाहिए. मुझे लगता है कि लोगों को अब समझना होगा कि राजा खुद के साथ एक व्यापक प्रयोग में लगे हुए हैं."

और विश्वनाथ प्रताप सिंह राजनैतिक संभावनाओं की कीमत पर जिस तरह आत्ममुग्ध होकर नैतिकता और आध्यात्मिकता के प्रयोग करने में लगे हुए हैं उससे यह धारणा तेजी से बन रही है कि लगातार बढ़ते असर के बावजूद उनका आंदोलन बड़बोले सिद्धांतों का प्रदर्शन मात्र ही है. कुल मिलाकर उनकी छवि नकारात्मक ही है. और इसके लिए कारणीभूत है उनका पेचीदा व्यक्तित्व जिसमें कई विरोधाभास दिखाई पड़ते हैं. वे राजीव को उखाड़ फेंकना चाहते हैं पर सत्ता में नहीं आना चाहते; राजीव को चुनौती देते हैं फिर भी अपने को उनका विकल्प नहीं मानते. विपक्षी दलों की एकता चाहते हैं लेकिन

भवान सिंह

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उलझे विचार

अभी भी अपने को विपक्ष के साथ आत्मसात नहीं कर पाए; वे एक विकेंद्रित और खुले-बाजार की अर्थव्यवस्था के पक्षधर हैं पर उनका यह भी कहना है कि वामपंथी दल उनके स्वाभाविक साथी हैं.

असल में जनमोर्चा के दूसरे नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह की इसी छवि को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं और इस प्रयास की शुरुआत उन्होंने किसी और से नहीं बल्कि खुद विश्वनाथ प्रताप सिंह से ही की है. कुछ हफ्ते पहले उनके एक वरिष्ठ साथी ने उनसे चिरौरी की, वे कोई पद या सत्ता नहीं लेने का अपना विचार उछालना बंद करें. इस चिरौरी-विनती का असर विश्वनाथ प्रताप सिंह पर पड़ा भी. पिछले हफ्तेवाड़े यह उस समय जाहिर हुआ जब जनमोर्चा के 60 नेता और राज्यों के संयोजक नई दिल्ली में दो दिनों के लिए इकट्ठे हुए. उन्होंने फरमान जैसा एक आदेश जारी करके वी.पी. सिंह को निर्देश दिया कि कोई पद लेंगे या नहीं इस बाबत वे अपनी निजी राय देना बंद कर दें. आगे से उन्हें सिर्फ मोर्चा की ओर से ही बोलना होगा.

जैसा कि मोर्चा के एक सदस्य बताते हैं, "मुश्किल यह है कि राजा साहब अकेले चलने वाले व्यक्ति हैं. लेकिन किसी राजनैतिक संगठन में आप अकेले नहीं चल सकते संगठन की धारणा के विरोधाभासी व्यक्तिगत विचारों को आपको छोड़ना पड़ेगा. हमारी सारी जद्दोजहद उन्हें राजनैतिक नेता बनाने की है, जो कि वे हैं नहीं."

इसके जवाब में विश्वनाथ प्रताप सिंह की प्रिय उक्ति रही है, "मैं एक राजनैतिक व्यक्ति ही हूं. पर लोगों में राजनीति को पद से जोड़ कर देखने की गलत धारणा बैठ गई है. मेरा मानना है कि पद से राजनैतिक सत्ता का नाता टूट सकता है. इसे एक विशुद्ध जनांदोलन बनाया जा सकता है." और इसके बाद वे इस बात पर जोर देते हैं कि वे कभी पद नहीं लेना चाहते, यहां तक कि चुनाव भी लड़ना नहीं चाहते. फिर भी वे इस व्यवस्था को बदल डालेंगे.

यह एक ऐसी 'पवित्र राजनैतिक बकवास' है जिससे उनके समर्थक बिदक उठते हैं. लेकिन वे इस बात पर जोर देते हैं कि वी.पी. सिंह की ये बातें उनके दिल की आवाज हैं. मोर्चा के नेता आरिफ मुहम्मद खां कहते हैं, "अपने पूरे राजनैतिक जीवन में उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उन्हें देश का वैकल्पिक नेता मान लिया जाएगा. उन्होंने अपने को इस भूमिका में कभी देखा ही नहीं. यही वजह है कि इंका से निकाले जाने के वक्त तक वे राजीव को 'मेरा नेता' ही कहते रहे." सतपाल मलिक कहते हैं, "हरिद्वार में पहली रैली करने तक उन्होंने सचमुच यह सोचा भी नहीं था कि उन्हें इस कदर समर्थन मिलेगा. यह भूमिका मानो उन पर थोप दी गई."

उनके विश्वासपात्रों का कहना है कि एचडीडब्ल्यू पनडुब्बी सौदे की जांच की घोषणा करने के बाद उनके खिलाफ चले घृणित प्रचार के कारण उनका स्वाभिमान आहत हुआ और वही गुस्सा उनमें घुमड़ रहा है. उन्होंने उसी समय इसका बदला लेने की कसम खा ली थी. इसी प्रक्रिया में उन्होंने पाया कि उन्हें तो व्यापक राजनैतिक समर्थन हासिल है. चूंकि मुख्य रूप से वे एक नैतिक व्यक्ति हैं इसलिए उनके सामने एक धर्मसंकट उठ खड़ा हुआ: क्या उन्हें अपने नाम और प्रतिष्ठा की रक्षा जैसे एक नितांत व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए अपने राजनैतिक समर्थन का प्रयोग करना चाहिए.

उनके घाव गहरे और शायद अमिट हैं. यह पनडुब्बी सौदे की जांच की घोषणा के बाद ही जाहिर हो गया था. उस दिन संसद में उन पर बूटा सिंह और दिनेश सिंह ने हमला किया. उनकी देशभक्ति पर शंका उठाई गई. उसी दिन शाम को वे अपने सरकारी बंगले के एक

चूंकि मुख्यतः वे एक नैतिक व्यक्ति हैं इसलिए उनके सामने बहुत बड़ा धर्मसंकट उठ खड़ा हुआ: क्या उन्हें सिर्फ अपना नाम और प्रतिष्ठा बचाने जैसे निजी उद्देश्य के लिए ही इस राजनैतिक समर्थन का उपयोग करना चाहिए

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लेकिन उनके खेमे के नेताओं को पता है कि वी.पी. सिंह के रूप में उन्हें एक ऐसी मशीन मिल गई है, जिसमें करिश्माई दम है. वे एक ऐसा राजनैतिक चेक हैं जिसे भुनाया जा सकता है. इसलिए वे इस चेक को बरबाद नहीं होने देना चाहते

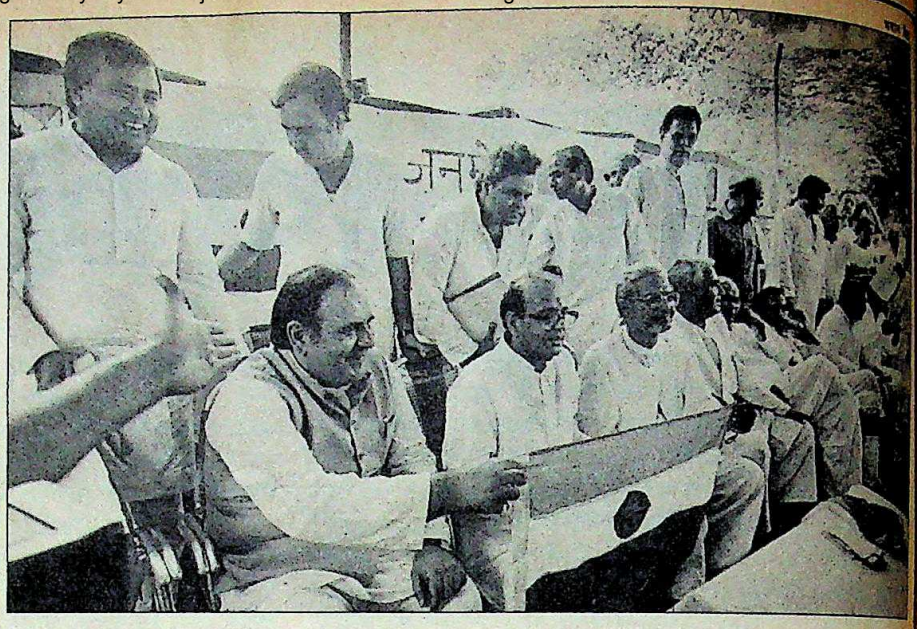

जनमोर्चा का झंडा दिखाते वी.पी. सिंह और अन्य लोग

सामान्य साज-सज्जा वाले कमरे में बैठे हुए थे. उनकी आंखों में तिरस्कार का भाव था. अपनी आदत के अनुसार मुलाकाती का स्वागत बड़ी विनम्रता से करने के बजाय वे अपनी कुर्सी से झटके से उठे और खिड़की की ओर इशारा करते हुए अस्वाभाविक तौर पर ऊंची आवाज में बोले, "बगीचे में उस पेड़ को आप देख रहे हैं? क्या उस पेड़ को आपने देखा? मेरी पत्नी और मैं उसी पेड़ के नीचे एक तंबू डालकर रह सकते हैं और वहीं रहकर हम एक लंबी लड़ाई लड़ सकते हैं. उन्होंने मुझे समझने में भूल की है. वे भूल गए कि जनता शासन के दौरान जब मैं जेल गया था तब मैंने बाहर का नहीं बल्कि जेल का ही खाना खाया. मैं फर्श पर ही सोता था और बीमार पड़ गया और मैंने दूसरे कंबल की मांग नहीं की."

उनकी यह प्रतिक्रिया पूरे तौर पर उनके चरित्र के अनुकूल ही थी. विश्वासघात का आरोप तो दूर रहा, कोई भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा दे तो वे तिलमिला उठते हैं, गुस्से से उबल पड़ते हैं. ये असली 'मिस्टर क्लीन' इतने जिद्दी, अपनी छवि के प्रति इतने सचेत हैं कि किसी उद्योगपति से भोज का निमंत्रण भी कभी नहीं स्वीकार करते. बंबई जैसे बड़े शहरों के प्रवास के दौरान वे पांच सितारा होटलों की बजाय हमेशा सरकारी अतिथि-गृहों में रुकते रहे हैं. वे सरकारी वाहनों के सरकारी और व्यक्तिगत उपयोग में हमेशा फर्क करते रहे.

हर हाल में वे एक गैर-राजनैतिक सनकी, आत्ममुग्ध, हठी, न झुकने वाले, पूरी तरह नैतिक और जल्दबाजी में रहने वाले व्यक्ति हैं. जिस किसी पद पर वे रहे और जिन संगठनों से वे जुड़े रहे हर जगह उन्होंने यही छाप छोड़ी है. वित्तमंत्री के रूप में उनकी हठवादिता के कारण उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगियों को पर्याप्त परेशानी में पड़ना पड़ता था. उद्योगपतियों पर छापों के दौरान उन्होंने अच्छे या बुरे, प्रतिष्ठित या शक्तिशाली राजनैतिक संबंधों वाले उद्योगपतियों में कोई फर्क नहीं किया. उन्होंने कमतर अपराधों वाले मामलों में भी छापे मारने का आदेश दिया. सिर्फ इतने पर ही वे रुके नहीं रहे. तब के उद्योगमंत्री नारायणदत्त तिवारी की सलाहों को अनदेखा कर सीमाशुल्क और आयकर के मामलों में विवादास्पद 20 औद्योगिक घरानों की उन्होंने एक 'काली सूची' ही बना डाली.

वी.पी. सिंह इन खासियतों को राजनीति में ले आए. उन्होंने अपने लिए वाम बनाम दक्षिण का कुख्यात बावेला मोल ले लिया. उनके साथियों ने सलाह दी कि उन्हें गैर-साम्यवादी विपक्षी खेमे में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते भाजपा के नेताओं अटलबिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी से मिलना चाहिए. लेकिन अपनी कार्यशैली के अनुरूप राजा साहब भाजपा नेताओं को अपने दूतों के जरिये टटोलते रहे कि वे उनके बारे में क्या सोचते हैं. वे उनसे खुद मिलने से कतराते रहे. इस तरह उन्होंने यह धारणा पैदा कर दी कि जनमोर्चा विपक्षी एकता के अपने घोषित उद्देश्य की राह में खुद ही एक बाधा है.

बहुआयामी व्यक्ति होने के नाते वी.पी. सिंह के व्यक्तित्व में एक और नाजुक मनोवैज्ञानिक दरार है. उनकी नैतिकता और शायद सेवाभाव भी महात्मा गांधी की देन है. वे भूदान आंदोलन के कट्टर समर्थक रहे हैं. इसीलिए उन्होंने हमेशा सामंती राजा की अपन छवि को धोने की कोशिश की है. लेकिन वे व्यवहार अभी भी राजा की ही तरह करते हैं.

अपना सामंती चोला उतार फेंकने की कोशिश में सामंत विरोधी वी.पी. सिंह मोर्चा नेताओं की सलाह को दरकिनार करते हुए प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी और भाजपा सहित दूसरे 'दक्षिणपंथी' दलों से कोई मेलजोल न रखने जैसे घिसे-पिटे राग ही अलाप रहे हैं. वे मजदूरों की रैलियों में शामिल होते हैं. बतौर वित्तमंत्री भी उन्होंने गरीबों के लिए कर्ज-मेलों की धारणा का समर्थन किया था. हालांकि बौद्धिक रूप से वे बाजारों की प्रतिस्पर्द्धा वाली अर्थव्यवस्था के हिमायती हैं पर खुलेआम ऐसा कहने में उन्हें संकोच है. वित्तमंत्री पद पर रहते वक्त उन्होंने सरकारी खर्चों में कटौती का समर्थन किया था और ऐसे क्षेत्रों की शिनाख्त भी की थी जहां यह खर्च कम किया जा सकता है. वे सरकारी क्षेत्र की नाकारा इकाइयों को बंद करने के भी पक्षधर थे. लेकिन इस विषय पर खुलेआम मुंह खोलने से वे परहेज करते हैं. इसके बावजूद 'राजा साहब' कहलवाना उन्हें भाता है. वे निरंकुश हैं. उनके निजी स्टाफ में इलाहाबाद के नौकरों की भरमार रहती है जो मालिक के इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं.

वी.पी. सिंह पर एक आरोप यह भी है कि अपनी ईमानदारी के बावजूद उत्तर प्रदेश के उनके मंत्रिमंडल में खराब छवि वाले राजनीतिक भरे पड़े थे. इनमें एक कृष्ण गोयल हैं. उन्हें पिछले विधानसभा चुनावों में इंका ने टिकट नहीं दिया था इसलिए कुछ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

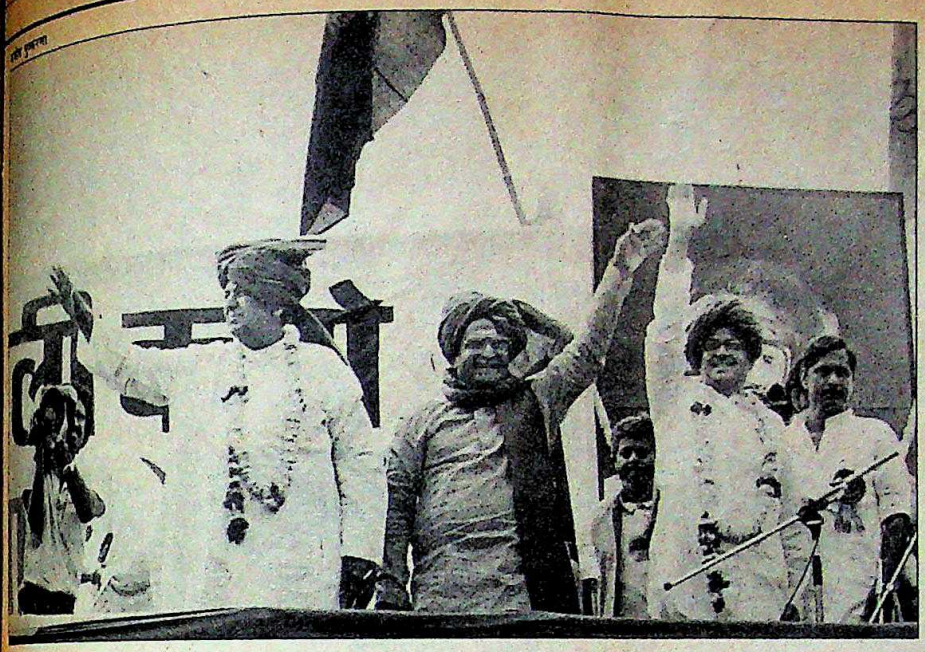

दिल्ली में हुई विपक्षी रैली में देवीलाल, रामराव और वी.पी. सिंह

अभी तक वी.पी. सिंह ने एक सैनिक और कार्यकर्ता का काम ही किया. लेकिन अब रूपांतरण की अंतिम घड़ी आ गई है. अब उन्हें कवच के अंदर आराम से रहने की जगह अपने डैनों के बल पर उड़ान भरने की क्षमता की परीक्षा करनी है

महीनों से वे बराबर वी.पी. सिंह से चिपके हुए हैं. मित्रों का मानना है कि राजा साहब को अपनी पसंद-नापसंद का काफी ख्याल रहता है और विश्वासपात्रों की कमजोरियों की वे अक्सर अनदेखी करते हैं. वित्त मंत्रालय में उन्होंने तमाम परिपाटियों को किनारे कर दिया था. विनोद पांडे को राजस्व सचिव और भूरेलाल को प्रवर्तन निदेशालय का प्रमुख बनाते वक्त उन्होंने अपने सलाहकारों की एक नहीं मानी.

दरअसल उन्होंने अपनी हैसियत इस कदर बना ली थी कि मंत्रिमंडलीय सहयोगी भी उनसे बात करते डरते थे. पर उन्हें इसमें आनंद आता था. आलोचक बताते हैं कि विद्याचरण शुक्ल और वरुण नेहरू समेत आज जो लोग उन्हें घेरे हुए हैं, जरूरी नहीं पाक-साफ छवि वाले ही हों. लेकिन वी.पी. सिंह को उन पर भरोसा है. पर ऐसा कब तक? उनके एक सहयोगी मजाक में कहते भी हैं, "कई बार उन्हें लगता है कि उनके छूते ही हर चीज साफ-सुथरी हो जाएगी और नेता लोग चाहे उनका पुराना रुतबा कैसा भी रहा है, उनके संपर्क में आते ही ईमानदार हो जाएंगे." उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बीरबहादुर सिंह कहते हैं, "राजा साहब अव्वल दर्जे के पाखंडी हैं. वे न सिर्फ भ्रष्ट लोगों से घिरे हुए हैं बल्कि उनका अपना रिकार्ड भी उतना साफ नहीं जितना वे दावा करते हैं."

लेकिन उनके खेमे के नेताओं को पता है कि वी.पी. सिंह के रूप में उन्हें एक ऐसी राजनैतिक मशीन हाथ लगी है जिसमें करिश्मा कर दिखाने का दम है. इसीलिए वे उन्हें बदलने, हकीकत की पहचान कराने और अधिक कारगर नेता बनने के लिए दबाव डाल रहे हैं. उन्हें मालूम है कि वे भुनाए जा सकने वाले राजनैतिक चेक हैं. इसलिए वे इसे खाली भी नहीं जाने देना चाहते. ज्यों ही वी.पी. सिंह में बदलाव आएगा, जनमोर्चा और उसकी छवि भी बदलेगी. वे उत्तर भारत में अभी भी अकेले ऐसे नेता हैं जो जहां जाते हैं वहीं भीड़ उमड़ पड़ती है. पिछले आठ महीनों में उन्होंने उत्तर-पूर्वी राज्यों को छोड़ प्रायः हर राज्य का दौरा किया. उत्तर भारत में 25 बड़ी रैलियों में वे एक करोड़ से अधिक लोगों को संबोधित कर चुके हैं. आश्चर्य है कि उत्तर भारतीय होने पर भी वे केरल और तमिलनाडु में भारी भीड़ खींचने में कामयाब रहे. विपक्षी दलों के लिए वे अभी भी सबसे महत्वपूर्ण वक्ता है.

वी.पी. सिंह को मिले व्यापक जनसमर्थन के मद्देनजर जनमोर्चा ने अब प्रायः हर राज्य में अपने संयोजक नियुक्त कर लिए हैं. सत्ताधारी इंका हालांकि वी.पी. सिंह का विरोध करती है, पर मोर्चे के अधिकांश नेता पूर्व इंकाई हैं. लेकिन राजनीति में उनके अड़ियल रवैये के चलते कई विपक्षी नेता उनसे दूर हो गए हैं. उत्तर प्रदेश में पूर्व राष्ट्रीय संजय मंच के एक विद्रोही विधायक अकबर अहमद कहते हैं, "वी.पी. सिंह हर किसी को अपने सामने झुकाना चाहते हैं. वे ऐसे फरमान जारी करते हैं जिन्हें किसी लोकतांत्रिक दल में स्वीकार नहीं किया जा सकता." हालांकि इन आलोचनाओं में से ज्यादातर सही हैं पर कुछ तो निश्चित रूप से विपक्षी नेताओं की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं पर वी.पी. सिंह के मंडराते खतरे से उपजी हैं.

लेकिन वी.पी. सिंह को सबसे बड़ी अंदरूनी ताकत एक ही बात से मिलती है. लोगों को लगता है कि आज की राजनीति में लगभग अनुपलब्ध एक चीज उनके पास है और वह है—ईमानदारी. उन पर खुफिया ब्यूरो और फेयरफैक्स आयोग जैसी कई जांचें बैठाई गई हैं. केंद्र ने उन्हें भ्रष्ट साबित करने के लिए अपने पूरे पुलिस बल को झोंक दिया. उनकी संपत्ति, ट्रस्ट, पारिवारिक कोष, बेटे के कैरियर सभी की बारीकी से जांच की गई.

लेकिन उनकी साख पर कोई आंच नहीं आई है. उनका कहना सही साबित हुआ है. उन्हें राजीव गांधी के बराबर राष्ट्रव्यापी मान्यता शायद नहीं ही मिल पाई पर एक नतीजा तो साफ है. नेहरू और इंदिरा गांधी के जमाने में कोई ऐसा नेता नहीं था जिसे विकल्प माना जाता रहा हो पर वी.पी. सिंह की आज भी राजीव के एकमात्र विकल्प के रूप में चर्चा है. इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता, भले ही उनके रुख की कितनी ही आलोचना क्यों न होती रहे.

तीन साल पहले औद्योगिक घरानों पर कर चोरी के छापे मारने के कारण वी.पी. सिंह की तुलना में राजीव को कम ही लोग जानते थे. पर अपनी छवि निखारने के लिए राजीव के पास सरकारी प्रचार तंत्र और एक जेबी राजनैतिक दल था. वी.पी. सिंह के पास दोनों में से एक भी नहीं है. लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि उनकी छवि बनने की प्रक्रिया बखूबी चल पड़ी है. वी.पी. सिंह अब अपनी निजी मजबूरियों को तोड़ रहे हैं जबकि उनके समर्थक उन्हें संभव कर दिखाने की कला में खींच लाने के लिए तुल गए हैं.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अफगान मसला

होम करते हाथ जले

कूटनीति के मोर्चे पर भारत की खूब भद पिटी

खबर ने मानो तहलका मचा दिया. 8 फरवरी को मिखाइल गोर्बाचेव ने अचानक ही घोषणा कर डाली कि मई तक सोवियत फौजें अफगानिस्तान से लौटना शुरू कर देंगी बशर्ते जिनेवा में होने वाली बातचीत से कोई समझौता निकल आए. सभी देश इससे चौंक उठे. पर नई दिल्ली में जैसे इसका कोई असर ही नहीं हुआ. गोर्बाचेव की इस धमाकेदार घोषणा का पूरा का पूरा मसौदा 36 घंटे पहले ही चुपचाप भारत सरकार को थमा दिया गया था.

पर इस कूटनीतिक रियायत का अर्थ साउथ ब्लॉक या प्रधानमंत्री सचिवालय ने शायद यह लगाया कि आठ साल पुराने अफगान मसले में भारत की भूमिका निभाने का समय आ गया है. अब उसे महज तमाशबीन बनकर नहीं रहना होगा. पर इस सौदे में भारत बुरी तरह मात खा गया. अफगानिस्तान से रूसी फौजें वापस जाएं, इसमें भारत की दिलचस्पी स्वाभाविक है पर नई दिल्ली ने जिस तरह से इस मामले में टांग अड़ाई उससे कूटनीतिक तौर पर परेशानी ही हाथ लगी.

उसके बाद जो हुआ वह भी एक भारी दांव था. पहले अफगानिस्तान के हालात पर बातचीत के लिए पाकिस्तानी राष्ट्रपति जिया-उल-हक को दिल्ली आने का न्यौता देकर और फिर तुरंत ही निमंत्रण की जानकारी सार्वजनिक तौर पर लाकर साउथ ब्लॉक जानते-बूझते मुंह के बल गिरने की स्थिति में आ गया. जैसी कि आशंका थी, जिया ने निमंत्रण ठुकरा दिया. इस पर भी भारत नहीं चेता और घोषणा कर डाली कि वह अपने विदेश सचिव के.पी.एस. मेनन को प्रधानमंत्री का विशेष दूत बनाकर इस्लामाबाद भेजेगा. यह सच है कि जिया ने टेलीफोन पर हुई बातचीत में राजीव से कहा था कि वे खुद भारत नहीं आ सकते लेकिन अगर नई दिल्ली 'परस्पर निर्धारित किसी तारीख को' कोई दूत भेजे तो उसका स्वागत है. पर प्रधानमंत्री सचिवालय ने फिर उतावली दिखाई और घोषणा कर दी कि मेनन अगले ही दिन रवाना हो जाएंगे. उधर पाकिस्तान ने कह दिया कि यह तारीख उसके अनुकूल नहीं पड़ रही है. मेनन की रवानगी तुरंत स्थगित कर दी गई और साउथ ब्लॉक मुंह ताकता ही रह गया.

कूटनीतिक और क्षेत्रीय हिसाब से देखें तो भारत को अफगानिस्तान की हालत पर अपना नजरिया जताने का पूरा-पूरा हक है. पर भारतीय विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अफसर मानते हैं कि मुद्दे को गलत ढंग से निबटाने की कोशिश की गई जिससे कूटनीतिक नौसिखियापन ही झलकता है. इससे प्रधानमंत्री के सलाहकारों की करतबबाजी दिखाने की बढ़ती आदतें भी उजागर होती हैं. सच यह है कि विदेश विभाग की इस मामले में एक नहीं चली. आला सूत्रों के मुताबिक निमंत्रण के मामले में प्रधानमंत्री सचिवालय ने विदेश विभाग को दरकिनार कर दिया. एक वरिष्ठ अफसर का कहना है, "इससे कूटनीतिक तौर पर कोई कहर तो नहीं बरपा पर यह एक भारी चूक जरूर थी. गंभीर कूटनीति को करतबबाजी की वेदी पर कुरबान नहीं किया जाना चाहिए." आला सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री सचिवालय यह सुझाव देने की गंभीरता से सोच रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में अफगानिस्तान में भारतीय शांति सेना भेजी जाए. इस नीयत से तो अफगान मसले में भारत की सर्वमान्य भूमिका बनाने की कोशिशें चूर-चूर होनी लाजिमी हैं खास तौर पर तब जबकि मामले से इस्लामाबाद भी जुड़ा हुआ है.

इस समय दुनिया भर की नजरों में रूसी फौजों की वापसी के लिए होने वाले किसी समझौते में पाकिस्तान सबसे बड़ी बाधा है. पिछले हफ्ते की जिनेवा वार्ताओं में पाकिस्तान के अड़ियल रवैये की वजह से ही समझौता टल गया. पाकिस्तान का कहना था कि सोवियत फौजों की वापसी से पहले अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार बनाई जाए. पाकिस्तान ने यह रवैया अमेरिका के काफी दबाव के बाद अपनाया. अफगानिस्तान के मुद्दे पर वह पिछले आठ साल से पाकि-

प्रशांत पंजियार

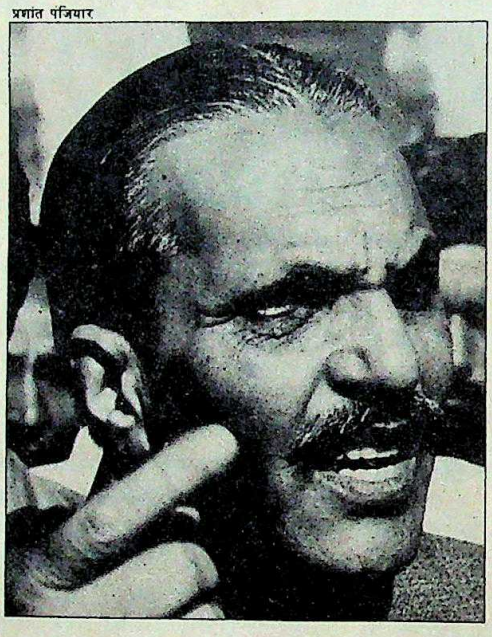

राष्ट्रपति जिया को अफगानिस्तान के मसले पर दिल्ली आने का न्यौता देकर फिर उसकी सार्वजनिक घोषणा करके राजीव मुंह के बल गिरने की स्थिति में आ गए हैं

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

स्तान की पीठ ठोंकता आया है. पर इससे पहले कि जिया अपने ही जाल में फंसते, उन्हें भारत को नीचा दिखाने का बना-बनाया मौका हाथ लगा. भारत के निमंत्रण पर प्रतिक्रिया पूछे जाने पर जिया ने मजाक किया, "क्यों? क्या इन दिनों वहां कोई क्रिकेट मैच चल रहा है?"

यह उम्मीद करना बेमानी ही था कि जिया अफगान मसले पर बातचीत के लिए नई दिल्ली आएंगे और वह भी ऐसे मौके पर जब पूरी जिनेवा वार्ता पाकिस्तान के इर्दगिर्द ही घूम रही हो. एक पाकिस्तानी कूटनीतिक सूत्र के अनुसार, "किसी नए विचार का निश्चय ही स्वागत है पर आठ साल चुप रहने के बाद अब भारत अगर सोचता है कि वह ईमानदार बिचौलिए की भूमिका निभा सकता है तो उसका समय बीत चुका है.

जाहिर है कि अफगानिस्तान के मामले में हाथ डालने से पहले भारत ने अपने पहले हुए कूटनीतिक नुकसान का भी लेखा-जोखा किया होगा. दिसंबर 1979 में जब से सोवियत टैंक काबुल में घुसे हैं, भारत की लगातार चुप्पी को यही अर्थ लगाया जाता रहा है कि वह पाकों की कार्रवाई का समर्थन कर रहा है. संयुक्त राष्ट्र में हर साल ऐसे मौके पर जब सोवियत हस्तक्षेप की निंदा का रस्मी प्रस्ताव रखा जाता तो भारत हमेशा उससे कन्नी काट लिया करता था. उधर पेशावर से अपनी गतिविधियां चला रहे मुजाहिदीन, जिन्हें काबुल की नई सरकार में सबसे ज्यादा नुमाइंदगी मिलने की संभावना है, भारत को शक की निगाह से या अक्सर दुश्मन के रूप में ही देखते हैं.

भारत कह रहा है कि उसने अफगानिस्तान में रूस की मौजूदगी का कभी समर्थन नहीं किया. विदेश राज्यमंत्री नटवर-सिंह कहते हैं, "1980 में तत्कालीन सोवियत विदेशमंत्री ग्रोमिको जब नई दिल्ली आए थे तो श्रीमती गांधी ने उन्हें साफ-साफ बता दिया था कि भारत इस कार्रवाई के खिलाफ है. हम दूसरे मौकों पर भी उन्हें यह बात जता चुके हैं. गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भी हमने ऐसी ही घोषणाओं (जिनमें सोवियत संघ का नाम नहीं लिया गया था) पर दस्तखत किए थे. पर अफगानिस्तान में सोवियत संघ की मौजूदगी पर भारत का विरोध चूंकि निजी स्तर की वार्ताओं में ही जताया गया था इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वह कोई साख कायम नहीं कर पाया.

अफगान मसले पर भारत की कोशिशों को इसलिए भी अक्षम्य माना गया क्योंकि इस संबंध में उसकी गुपचुप कूटनीति भी कारगर रही है. रोम में भारत के राजदूत और धाराप्रवाह फारसी बोलने वाले अकबर खलीली कई बार अफगानिस्तान के निर्वासित बादशाह जहीर शाह से मिलकर साझा सरकार की अगुआई की संभावनाओं पर विचार-विमर्श कर चुके हैं. नटवर सिंह भी पिछले महीने रोम जाकर थोड़ी देर के लिए जहीर शाह से मिले थे पर अखबारों को उनके इस दौरे की भनक मिल गई थी. हालांकि शाह की वापसी अब मुजाहिदीन नेताओं को मंजूर नहीं है पर अधिकांश अफगान जनता उन्हें स्वीकार कर लेगी. इसलिए उनकी उम्मीदवारी से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता, खासतौर पर तब जबकि विद्रोहियों में इस बात को लेकर गंभीर मतभेद हैं कि सोवियत फौजों की वापसी के बाद बनी अंतरिम सरकार का स्वरूप क्या होगा. भारत सरकार ईरान में रह रहे विद्रोहियों से भी लगातार संपर्क बनाए हुए है. और साथ ही दुनिया भर में रह रहे अफगान बुद्धिजीवियों से बातचीत जारी रखी है.

यू.एन.आई.

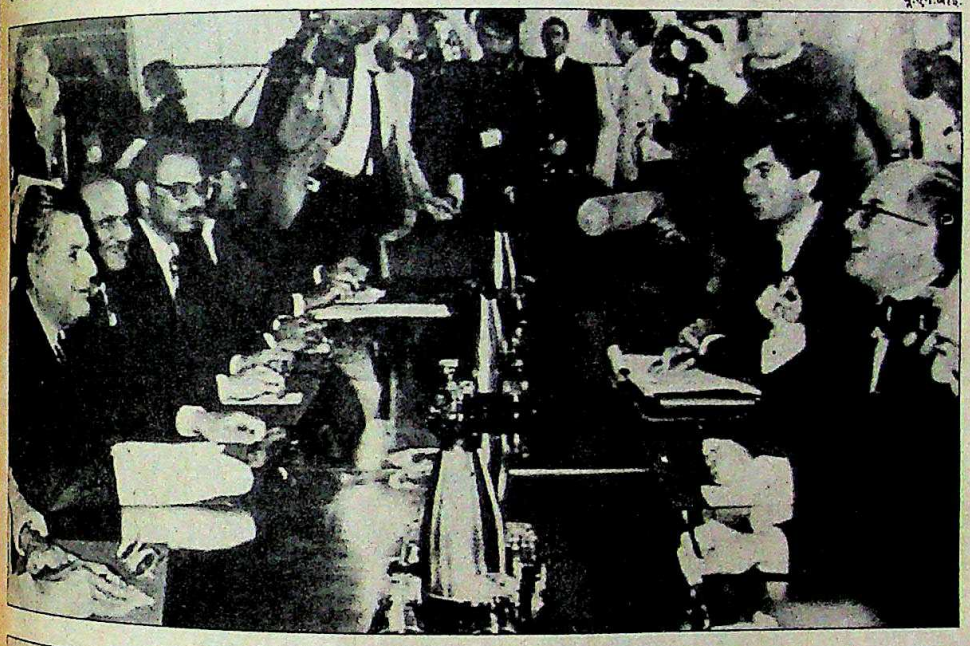

रूसी सेना की वापसी से पहले अफगानिस्तान में एक अंतरिम सरकार बनाने की पाकिस्तानी जिद उसे अलग-थलग कर देगी और भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी

भारत की इस पोशीदा कूटनीति की वजह से ही रूस, अमेरिका और काबुल की नजीबुल्ला सरकार उसकी भूमिका की तारीफ करते रहे हैं. राजीव की पिछली वाशिंगटन यात्रा के दौरान राष्ट्रपति रेगन ने उनसे कहा था कि अगर भारत सोवियत संघ पर अपने असर का इस्तेमाल कर उसे अफगानिस्तान से लौटने के लिए राजी कर ले तो उसका स्वागत है. अफगान राष्ट्रपति नजीबुल्ला, सोवियत उप-विदेशमंत्री इवोर वारोंत्सोव और अमेरिकी उपविदेशमंत्री माइकल आर्मकोस्ट की एक के बाद एक हुई नई दिल्ली पर साउथ ब्लॉक ने इस सबका शायद कुछ ज्यादा ही गलत अर्थ निकाल लिया और इसे अफगान मुद्दे पर ज्यादा असरदार भूमिका निभाने का निमंत्रण मान लिया. साउथ ब्लॉक का कहना है कि आर्मकोस्ट ने उन्हें इस्लामाबाद से इस सिलसिले में बातचीत के लिए कहा था. पाकिस्तान के कूटनीतिक सूत्र भी उतने ही जोर-शोर से बताते हैं कि उन्होंने आर्मकोस्ट से खास तौर पर जब इसके बारे में पूछा तो उन्होंने ऐसा कोई सुझाव देने की बात से इनकार किया था.

सचाई जो भी हो, इतना साफ है कि फूहड़ों की तरह जिया को न्यौता देकर भारत

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गर्मियों में जब आपकी त्वचा महसूस करे कांटों-सी चुभन...

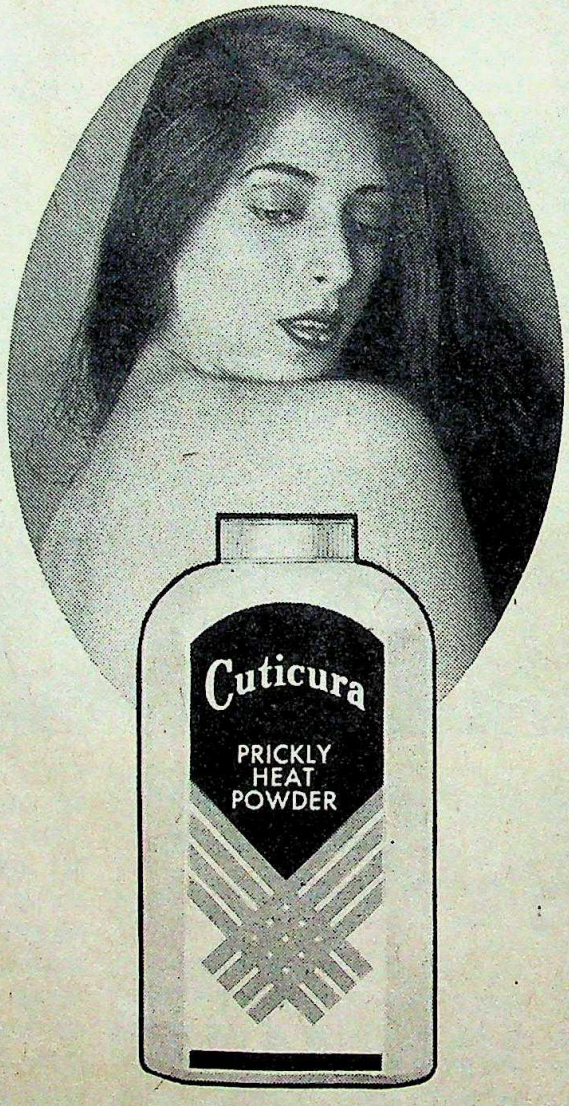

तब चुभन हटाए
राहत का एहसास दिलाए

नया क्यूटीक्युरा
प्रिकली हीट पाउडर

Orbit/MP—PHP/147-87—H

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ने कूटनीतिक लाभ हाथ से निकल जाने दिया है. वह भी ऐसे समय जब काबुल में कैसी भी सरकार बने उसमें उसकी जायज रुचि है. मगर काबुल में नई सरकार के प्रति भारत और पाकिस्तान की रुचि उसके सामरिक संबंधों से भी जुड़ी हुई है. ऐतिहासिक रूप से काबुल की सरकार पाकिस्तान के मुकाबले भारत के ज्यादा करीब रही है. पिछले 40 साल से भारत अफगानिस्तान को सिंचाई योजनाओं, अस्पतालों, विकास योजनाओं में आर्थिक सहायता देता रहा है और तकनीकी सलाहकार भी भेजता रहा है.

मैत्री रखने वाली ऐसी सरकार भारत के सामरिक हितों में भी है क्योंकि इससे पाकिस्तान को अपने पश्चिमी हिस्से पर अधिक ध्यान देना पड़ेगा. वास्तव में, पाकिस्तान संबंधी गुप्त सूचनाएं जुटाने में अफगानिस्तान भारत के लिए उपयोगी क्षेत्र रहा है. मगर फिलहाल सोवियत संघ की वापसी से भारत को सबसे बड़ी आशा यह है कि इससे अमेरिका की नजरों में पाकिस्तान का सामरिक महत्व कम हो जाएगा.

इस मायने में इस्लामाबाद की हालत पतली हो गई है. अमेरिका अपने क्षेत्रीय सहयोगी पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा है कि वह जिनेवा वार्ता के ताजा दौर में समझौता मंजूर कर ले. जहां तक अमेरिकी प्रशासन का सवाल है उसकी एक ही प्राथमिकता है कि सोवियत संघ अफगानिस्तान से बाहर निकले और राष्ट्रपति रेगन ऐसे इतिहास पुरुष के रूप में याद किए जाते रहें जिसने नामुमकिन कारनामा अंजाम कर दिखाया हो. इसलिए पाकिस्तान को वापसी पर राजी होना ही पड़ेगा. वह केवल इतना चाहेगा कि वहां उसे और मुजाहिदीनों को मान्य सरकार कायम हो. इस्लामाबाद को पाकिस्तान में रह रहे 30 लाख शरणार्थियों की वापसी की बड़ी चिंता है जो काबुल में उन्हें मान्य सरकार बनने पर ही लौटने पर राजी होंगे. इसके साथ ही इस्लामाबाद अमेरिकी सरकार पर दबाव डालेगा कि उसे हथियारों की सहायता जारी रहे. वह यह भी चाहेगा कि उसकी पश्चिमी सीमा पर भारत समर्थक या यहां तक कि फिर सोवियत समर्थक सरकार बनी न रहने पाए.

अफगानिस्तान के मसले पर भारत सरकार की पोशीदा कूटनीति की वजह से ही सोवियत संघ, अमेरिका और काबुल की नजीबुल्ला सरकार उसकी भूमिका की तारीफ करती रही हैं

पीआईबी

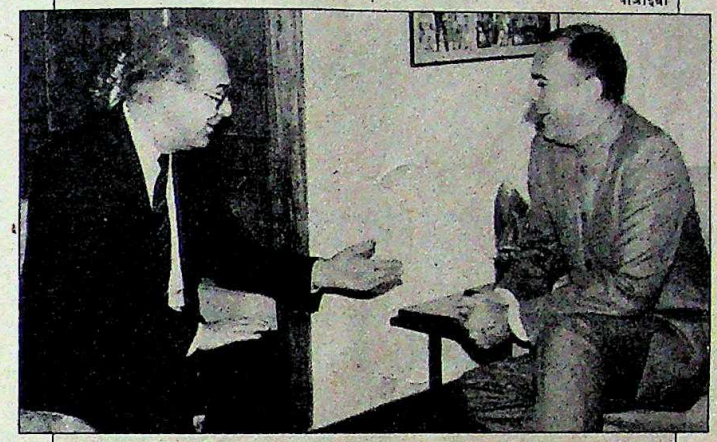

आर.के. शर्मा

पीआईबी

हाल में हुई बैठकों में राजीव (ऊपर से) वारोंत्सोव, आर्मकोस्ट और नजीबुल्ला के साथः भूमिका की तलाश

भारत का मत है कि सोवियत संघ की वापसी के बाद भी नजीबुल्ला की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान (पीडीपीए) का प्रभाव कम नहीं होगा. एक भारतीय अधिकारी के अनुसार, "पार्टी की काबुल पर पकड़ बेहद मजबूत है और उसके पास पास 1,50,000 हथियारबंद मिलीशिया सैनिक हैं. अफगानिस्तान में अब भी यह सबसे अधिक शक्तिशाली राजनैतिक ताकत है. इसके अलावा उनके पास खाद (अफगानिस्तान की गुप्तचर पुलिस) से संबद्ध 1,00,000 विश्वस्त व्यक्ति भी हैं." यहां तक कि अमेरिका भी अब इस बात को मान रहा है कि पीडीपीए को प्रतिनिधित्व दिए बिना नई सरकार बनाना संभव नहीं होगा.

इसलिए हाल की जिनेवा वार्ता से निकलने वाले नतीजे पर ही सब निर्भर करेगा. यदि पाकिस्तान की हठधर्मी की वजह से वार्ता असफल हुई तो भारत की भूमिका कारगर हो उठेगी और उसे इस्लामाबाद को हवा में चक्करघिन्नी खाते हुए देखने का सुख भी मिल सकेगा.

—विलीप बॉब और इंद्रजीत बधवार

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कार्टून: अजीत नाइनन

श्रीलंका

अलग सुर, अलग राग

कूटनीतिक खेल में तमिल मुक्ति चीतों का पलड़ा भारी

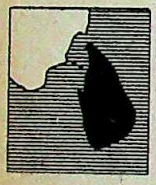

जयवर्द्धने सरकार इस साल की शुरुआत से ही वहां की जातीय समस्या का जैसा इलाज करने की कोशिश में लगी है उसे बायपास सर्जरी ही कहा जा सकता है. श्रीलंका की इस भयावह समस्या के इलाज के सभी परंपरागत तरीके बेकार साबित हो चुके हैं. पर हर डॉक्टर जानता है कि नया ऑपरेशन अक्सर कुछ नई पेचीदगियां पैदा कर देता है. श्रीलंका के मामले में तो ऐसे ऑपरेशन के बाद का असर खतरनाक साबित हो ही सकता है.

कोलंबो द्वारा समझौते के सहयोगी भारत को दरकिनार कर मुक्ति चीतों से सीधी, गोपनीय बातचीत करने के फैसले से साफ लगा कि श्रीलंका भारत को अलग करके खुद कूटनीतिक बढ़त हासिल कर लेना चाहता है. अगर यह अभियान सफल हो जाता तो श्रेय कोलंबो को ही मिलता.

पर आखिर में नतीजा यही निकला कि जातीय मामले में कोलंबो और नई दिल्ली ने अलग-अलग रुख अपना लिए और अब वे एक-दूसरे को मात देने की कोशिश में हैं. कोलंबो की गोपनीय चालबाजी का पता चलते ही भारत के उच्चायुक्त जे.एन. दीक्षित ने घोषणा की कि राजनैतिक समाधान की किसी भी कोशिश से भारत को अलग करने से 'गलतफहमी हो सकती' है. इसी के साथ नई दिल्ली भी श्रीलंका की तरह राजनैतिक समाधान के लिए मुक्ति चीतों से सीधी और गोपनीय बातचीत के तरीके पर उतर आई है. विदेश राज्यमंत्री नटवर सिंह ने इसे स्वीकार भी किया है.

सूत्रों के मुताबिक श्रीलंका के आंतरिक सुरक्षामंत्री ललित अतुलतमुदाली ने ही जयवर्द्धने को यकीन दिलाया कि वे मुक्ति चीतों से सीधी बातचीत करने की स्थिति में हैं और उधर से हरी झंडी मिलते ही उन्होंने और एक दूसरे मंत्री जेमिनी दिशानायके ने मुक्ति चीतों के नेता प्रभाकरन से बातचीत की प्रक्रिया शुरू भी कर दी. इस काम में तीन बिचौलियों—प्रभाकरन के स्कूल के दिनों के दोस्त और अमेरिका में रह रहे तमिल प्रवासी डॉ. सेल्वाकुमार, तमिल ईलम नेताओं से काफी संपर्क रखने वाले 'हिंदू' के पूर्व कोलंबो संवाददाता डी.बी.एस. जयराज और अखिल सीलोन तमिल कांग्रेस पार्टी के महासचिव कुमार पुन्नांबलम की मदद ली गई. कोलंबो ने मुक्ति चीतों के सामने एकमुश्त समझौते का प्रस्ताव रखा जिसके तहत उन्हें उत्तरी प्रांत की बागडोर सौंप दी जाएगी. इसके लिए एक अंतरिम प्रशासन कायम किया जाएगा जिसमें मुक्ति चीतों का बहुमत होगा. बस शर्त यही है कि वे पूर्वी प्रांत पर अपना दावा छोड़ दें.

दूसरी तरफ नई दिल्ली मुक्ति चीतों तक यह संदेश पहुंचाकर कि कोलंबो से चुपचाप किया गया उनका कोई भी समझौता भारत की मदद के बिना नाकाम रहेगा, इस प्रक्रिया में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है. विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी कहते हैं, "मुक्ति चीतों का आधार जाफना में ही है और (कोलंबो से) समझौता करने को वे प्रेरित हो सकते हैं लेकिन भारत की मदद के बिना वे अपना राजनैतिक मकसद प्राप्त करने की आशा नहीं कर सकते."

इस तरह नई दिल्ली मुक्ति चीतों को प्रांतीय परिषद के लटके पड़े चुनाव में हिस्सा लेने के लिए राजी करके उनके साथ खुद समझौता करने के फेर में है. जाहिर है कि मुक्ति चीतों की भागीदारी के बिना प्रांतीय परिषदों के चुनाव से कोई राजनैतिक मतलब नहीं सधने वाला. भारत सरकार मद्रास में अपने कटे पैर का इलाज करवा रहे मुक्ति चीतों के जाफना के कमांडर किट्टू की मार्फत बातचीत चला रही है. श्रीलंका में मुक्ति चीतों के दूसरे नंबर के नेता महात्या से उनका रेडियो संपर्क बना हुआ है.

लेकिन नई दिल्ली अब सौदेबाजी की वैसी स्थिति में नहीं है जैसी पिछली जुलाई में 'ऑपरेशन पवन' के शुरू होने के समय थी. श्रीलंका में अनुमानित 1,25,000 भारतीय शांति सैनिकों की मौजूदगी के बावजूद मुक्ति चीते उनके अंकुश से बाहर हैं. प्रभाकरन ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत सरकार से बातचीत तभी हो सकती है कि जब शांति सेना 'सैनिक कार्रवाई से पूर्व' के स्थानों पर लौट जाए और उत्तरी प्रांत के अंतरिम प्रशासन में मुक्ति चीतों को बहुमत की भागीदारी देने का उन्हें यकीन दिला दिया जाए. प्रभाकरन ने नई दिल्ली से कोई समझौता होने की सूरत में अपने तमाम हथियार डालने से भी इनकार कर दिया है.

मुक्ति चीते आज भारत और श्रीलंका को आपस में भिड़ाने की स्थिति में पहुंच गए हैं तो सिर्फ इसलिए कि दोनों सरकारें अलग-अलग राग अलापने लगी हैं

इसका अर्थ यह हुआ कि मुक्ति चीते अब दोनों पक्षों को एक दूसरे से भिड़ाने की हालत में पहुंच गए हैं. यह स्थिति सिर्फ इसीलिए संभव हो पाई है क्योंकि नई दिल्ली और कोलंबो की सरकारें अलग-अलग राग अलापने लगी हैं. इस प्रक्रिया में मुक्ति चीतों के साथ यदि कोई समझौता होता है तो निश्चय ही वह स्वागत योग्य होगा. पर श्रीलंका में 400 भारतीय सैनिकों का बलिदान अब जैसे बेमतलब होता जा रहा है.

—दिलीप बॉब

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

आखिर क्यों ज्यादा से ज्यादा लोग शादी-ब्याह के अवसर पर बीनाटोन क्वार्ट्ज टी.वी. ही उपहार में दे रहे हैं... ।

...सामंजस्य के लिए जिसकी गारंटी है।

अपने प्रिय से प्रिय व्यक्ति को दीजिए वह उपहार जो सर्वोत्तम हो। और अनूठे बीनाटोन क्वार्ट्ज टी वी से बेहतर उपहार भला क्या हो सकता है। रंगों की मोहकता तथा तस्वीर की स्पष्टता का बेमिसाल सामंजस्य और पिक्चर ट्यूब पर 3 साल की गारंटी भी। अपने निकटतम रंगीन/ब्लैक ऐण्ड व्हाइट टी वी के डीलर के यहां बीनाटोन के विविधतम मॉडलों को देखिए।

एक ऐसा उपहार जिसके लिए आप हमेशा याद किये जाएंगे।

बीनाटोन के सभी उत्पादनों को मास्टरकेयर का सहारा प्राप्त है जो बस एक फोन करते ही देशव्यापी बिक्री-बाद-सेवा प्रदान करते हैं।

Binatone

बनावट बेमिसाल, साथ निभाए सालोंसाल

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

बीनाटोन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लि., 23/4788-90 अंसारी रोड, दरियागंज, नयी दिल्ली-110002.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

एक कैन
30,000
कि.मी. तक
असरदार

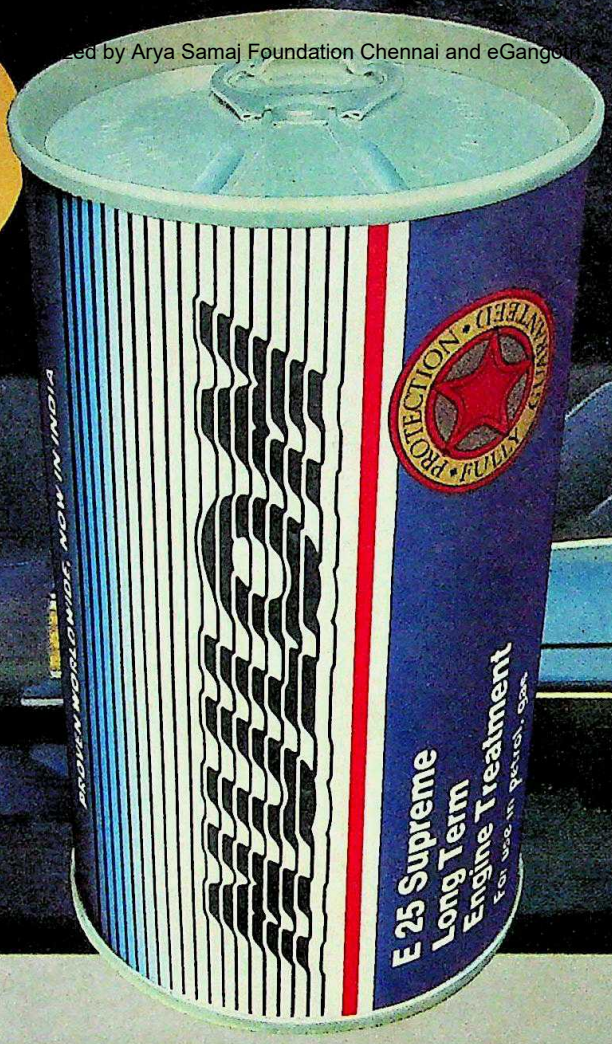

अब भारत में भी

न्यूलॉन
विश्व का सबसे लोकप्रिय
इंजन ट्रीटमेंट

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

...नई तकनीकी चमत्कार जिससे आपके वाहन को अधिक शक्ति–अधिक माइलेज मिले और ...बरसों–बरस चले

न्यूलॉन–इंजन के पुर्ज़ों को रगड़ से बचाने का विशेष उपाय

इंजन के कल-पुर्ज़ों की सतह पर रगड़ और घिसाव के कारण छोटे-छोटे निशान या खरोंच बन जाते हैं जिन्हें आँखों से नहीं देखा जा सकता. हालांकि मोटर ऑयल तकनीकी दृष्टि से काफ़ी विकसित हो चुके हैं पर वे निशानों या खरोंचों से होने वाले नुक़सान को नहीं रोक पाते और इसी कारण इंजन की शक्ति में कमी आती है, ईंधन की खपत बढ़ जाती है और इंजन की टूट-फूट बढ़ जाती है.

न्यूलॉन एक क्रांतिकारी इंजन ट्रीटमेंट है जो संसार भर में तेज़ी से लोकप्रिय हुआ है. न्यूलॉन प्रॉडक्ट्स (ऑस्ट्रेलिया) प्रा.लि. के तकनीकी सहयोग से यही न्यूलॉन इंजन ट्रीटमेंट अब भारत में भी उपलब्ध है.

न्यूलॉन में है संसार का सबसे अधिक चिकनाहट वाला पदार्थ–पी.टी.एफ़.ई.* जब न्यूलॉन को इंजन ऑयल में डाला जाता है तो पी.टी.एफ़.ई. के कण इंजन के चलने वाले हिस्सों की सतह में पड़ी रगड़ या खरोंचों पर समान रूप से जमकर सुरक्षात्मक परत (फ़िल्म) बना देते हैं.

*पॉलीटेट्राफ्लुओरोइथाईलीन

इसी कारण, इंजन के पुर्ज़ों को रगड़ से बचाने का विशेष उपाय, न्यूलॉन, सभी प्रकार के वाहनों और स्थिर इंजनों के लिए आदर्श है.

मोटर रेस–कड़ी परख की सर्वोत्तम प्रयोगशाला

आज, कारों या वाहनों में जो भी अनेक सुविधा-साधन हैं, इनका विकास और परख रेस के दौरान हुआ है. और अब इसी सर्वोत्तम प्रयोगशाला का नया आविष्कार है–न्यूलॉन.

हाल ही में हिमालय कार रैली में 15 विजेता कार चालकों में से 8 ने अपनी सफलता के लिए न्यूलॉन इस्तेमाल किया.

संसार भर में अपनाया गया

न्यूलॉन–जापान, अमरीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण कोरिया तथा कई अन्य देशों में लोकप्रिय है. आज के इस दौर में कुछ ही ऐसे नए उत्पादन होते हैं जो अपनी ख़ासियत के कारण लोगों का नज़रिया ही बदल देते हैं. ऐसा ही विशिष्ट उत्पादन है–न्यूलॉन.

आज से ही न्यूलॉन अपनाइए. न्यूलॉन के बग़ैर इंजन की नहीं ख़ैर.

न्यूलॉन के कारगर होने का निश्चित सबूत

ऑस्ट्रेलिया में वी.सी. होल्डन कॉमोडोर सिडान कार पर यह सिद्ध करने के लिए परीक्षण किया गया कि न्यूलॉन इंजन ट्रीटमेंट वाकई कितना कारगर है?

इंजन के ऑयल में न्यूलॉन को मिलाकर कार को कुछ दूरी तक चलाया गया, फिर ऑयल पूरी तरह निकाल दिया गया. उसके बाद इस कार को सिडनी से मेलबोर्न तक चलाया गया, यानि 1031 कि. मी. की दूरी बग़ैर इंजन ऑयल के तय की गई.

न्यूलॉन की कार्यकुशलता का इससे बेहतर सबूत क्या होगा?

चेतावनी–उपरोक्त परीक्षण केवल प्रदर्शन के लिए था. न्यूलॉन निर्माता के अनुसार वाहन को सदा इंजन ऑयल डालकर ही चलाइए.

NULON

...जानकारी के लिए : न्यूलॉन इंडिया लि., न्यूलॉन हाउस, ईश्वर नगर, मथुरा रोड, नई दिल्ली-65

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लोहा बेचकर होटल खोलेंगे

महिंद्रा उजाइन स्टील (बिक्री लगभग 85 करोड़) साधारण किराए (500 से 600 रुपए प्रतिदिन) वाले होटलों की एक शृंखला देश भर में खोलना चाहती है. कंपनी ने हाल ही में अमेरिका की 'डेज इन' कंपनी (जिसकी अमेरिका में सस्ते लॉजों की एक शृंखला है) के साथ इस आशय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए. लेकिन अभी तक सरकार से इसकी अनुमति नहीं मिली है. कंपनी खुद भी अपना पहला होटल खोलने से पहले बाजार सर्वेक्षण करना चाहती है. वैसे अभी यह तय होना बाकी है कि पहला होटल कहां खोला जाएगा और इस शृंखला में कितने होटल खोले जाएंगे. इसी कारण पूंजी निवेश की योजनाएं अभी अधर में हैं लेकिन यह परिवर्तन कंपनी को लोहा उद्योग की मंदी से बचाने के लिए है.

डीसीएम में झमेला

डीसीएम के नए प्रबंधक कंपनी की हालत में सुधार करना चाहते हैं. एक ओर कंपनी पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय संस्थाओं का सहारा लेने की योजना बना रही है, वहीं श्रीराम घराने के कुछ सदस्यों का कहना है कि इस नई व्यवस्था से परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव को ही बढ़ावा मिल रहा है. ऐसी हालत में कंपनी का बंटवारा अवश्यंभावी है. लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि अब तो श्रीराम घराने का इस कंपनी पर नियंत्रण रह ही नहीं गया है. अब जो झगड़ा होगा वह वित्तीय संस्थाओं के बीच ही होगा. यह अंदेशा कितना सच निकलेगा यह देखना बाकी है. लेकिन पिछले एक वर्ष में ही कंपनी के 2,300 अधिकारियों में से 10 प्रतिशत कंपनी छोड़कर जा चुके हैं.

चादर से लंबे पांव

आठ सौ करोड़ रुपए के उत्पादन शुल्क के झमेले में फंसी इंडियन टुबैको कंपनी ने अब दूसरे क्षेत्रों में पूंजी लगाने का निर्णय लिया है. इस बार इसने पूंजी निवेश के लिए तिलहन को चुना है. कंपनी की अगले कुछ वर्षों में जोर-शोर से इस क्षेत्र में उतरने की योजना है. इस योजना की एक शोध और विकास इकाई भी बनाई जा रही है. उधर सरकार से संबंध सुधारने के लिए नई दिल्ली में एक दफ्तर भी खोला जा रहा है, जो शायद कर संबंधी अपनी मुश्किलों का समाधान ढूंढ़ने का ही इसका एक प्रयास है.

कड़वी दवा

दवा उद्योग की नई नीति को लेकर सरकार की बड़ी भद हो रही है. कुछ उत्पादों में मूल्य नियंत्रण से छूट मिलने के बाद दवा कंपनियों ने इनकी कीमतें लगभग दुगुनी कर दी हैं. कई मामलों में तो यह वृद्धि सौ फीसदी से भी ज्यादा है. सरकार के लिए यह निश्चय ही परेशानी में डालने वाली स्थिति है. दवा निर्माताओं से कीमतें कम करने को कहा जा रहा है. सरकार मूल्य नियंत्रण वाली दवाओं की कीमतें बढ़ाने की अनुमति नहीं दे रही. वैसे नई नीति के तहत इसकी इजाजत है. जैसे पुरानी नीति के तहत मेंसिलीन पर 40 प्रतिशत कीमतें बढ़ाने की छूट दी गई थी. नई नीति के तहत सीमा 100 प्रतिशत है. लेकिन सरकार के सामने और मूल्य वृद्धि के आवेदनों का ढेर लगा है.

फिसलता फायदा

भारतीय उद्योग में बढ़ती प्रतियोगिता के कारण कंपनियों के लाभ में भारी गिरावट आई है. 'सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी' द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार 704

चार्ट: बी.के. शर्मा

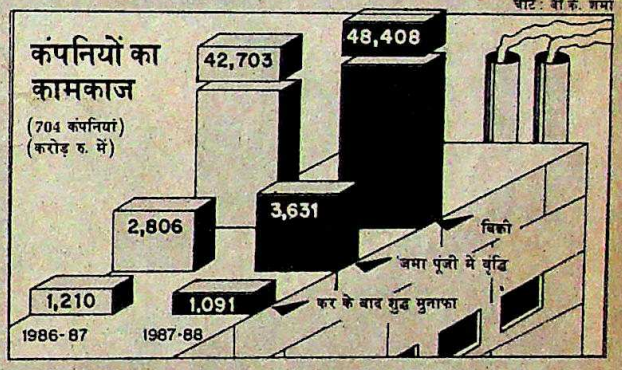

इकाइयों की बिक्री इस साल पिछले वर्ष के मुकाबले 13 फीसदी बढ़ी. लेकिन कर और ब्याज के बाद लाभ केवल तीन फीसदी ही बढ़े. कर अदायगी के बाद शुद्ध मुनाफा तो दस प्रतिशत घट ही गया. यह 1,210 करोड़ से 1,091 करोड़ रुपए रह गया. लाइसेंस नीति को उदार बनाने के बाद कंपनियों की जमा-पूंजी तेजी से बढ़ी है. यह 2,806 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,631 करोड़ रुपए हो गई है. यह वृद्धि लगभग 29 प्रतिशत है.

रियायत फिर भी नहीं

कारों के इंजन कितने तेल की खपत करते हैं, इस आधार पर उत्पाद कर तय करने के मामलों में सरकार खिलवाड़-सा ही करती रही है. लेकिन सबसे अजीब मामला प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स का है जिसने अपनी पद्मिनी कार को ईंधन खपत की क्षमता की जांच के लिए भेज दिया था. छह महीने पहले यह कार इस परीक्षा में खरी उतरी और कंपनी ने उत्पाद कर में रियायत का दावा किया. लेकिन उद्योग मंत्रालय ने उसे यह कहते हुए रियायत नहीं दी कि यह योजना सिर्फ नई कारों के लिए है.

कंपनी का कहना है कि मॉडल चाहे जो हो, कम ईंधन खपत की क्षमता वाला पैमाना एक ही होना चाहिए. पर सरकार अभी भी चुप्पी साधे हुए है क्योंकि मांग मान लेने का अर्थ कंपनी को 18 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ देना होगा.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बजट

सबको खुश करने की कोशिश

नारायणदत्त तिवारी का लोकोन्मुखी लेकिन महंगा बजट

हर तबके के लोग इस साल के बजट में करों का बोझ बढ़ने के अंदेशे से परेशान थे. पर बजट आया तो एकदम विपरीत प्रकृति का. ग्रामीण क्षेत्र के लिए भारी रियायतें दी गई हैं. कपड़ा और सीमेंट जैसे उद्योगों के लिए भी खुशखबरी थी. आयकर दाताओं को भी कुछ फायदा मिल गया. एक आर्थिक पंडित का मानना था कि, "यह सभी को खुश करने के लिए बनाया गया था. किसी को चाकलेट मिला, किसी को लालीपॉप."

इससे भी बढ़कर, यह संकेत मिलता है कि सरकार अब शून्य आधारित बजट बनाने के लिए खुद को तैयार कर रही है. अभी तक कई इंका शासित प्रदेशों में ऐसा बजट आ भी चुका है. मुकुंद आयरन के अध्यक्ष और पूर्व जनता सांसद वीरेन शाह ने कहा, "यह बजट 'वोट बैंक' को ध्यान में रखकर बना है." किसानों को दी गई रियायतों पर एक सरकारी वित्तीय संस्थान के प्रमुख ने कहा, "बजट में राजनैतिक तत्वों की प्रधानता है."

कार्टून: बी.के. शर्मा

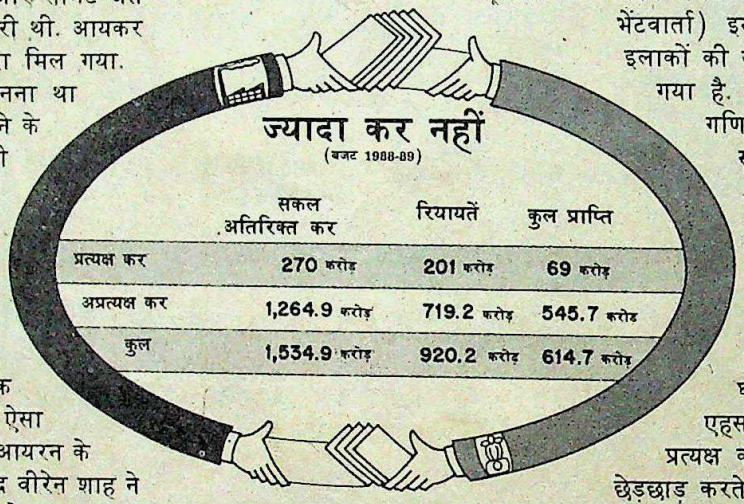

ज्यादा कर नहीं
(बजट 1988-89)

	सकल अतिरिक्त कर	रियायतें	कुल प्राप्ति
प्रत्यक्ष कर	270 करोड़	201 करोड़	69 करोड़
अप्रत्यक्ष कर	1,264.9 करोड़	719.2 करोड़	545.7 करोड़
कुल	1,534.9 करोड़	920.2 करोड़	614.7 करोड़

पर हो सकता है कि पूरे देश को खुश बनाया गया हो. 1988-89 के बजट पर वित्तमंत्री नारायणदत्त तिवारी की छाप दिखती है. तिवारी दिल से समाजवादी हैं. वे अपने बजट को लोकोन्मुख मानते हैं (देखें भेंटवार्ता) इसी कारण खेती और ग्रामीण इलाकों की जरूरतों को प्रमुख स्थान मिल गया है. यह बात इंका के राजनैतिक गणित के अनुरूप भी है क्योंकि सूखा वाले इस वर्ष में किसानों का मूड बहुत गरम है.

उन अनेक चीजों पर से करों में कटौती की गई है जिनका इस्तेमाल आम लोग करते हैं. इस प्रकार तिवारी ने अधिक-से-अधिक घरों में अपनी मौजूदगी का एहसास कराने की कोशिश की है. प्रत्यक्ष करों के मामले में कम-से-कम छेड़छाड़ करते हुए उन्होंने अप्रत्यक्ष करों में कटौती करके अचार, जैम,

बजट की मुख्य बातें

लोगों के लिए

- जायदाद कर के अंतर को अप्रत्यक्ष रूप से फिर से लागू किया गया है.
- आयकर छूट की सीमा बढ़ा दी गई है.
- अब से राष्ट्रीय बचत पत्र में किया गया पूरा निवेश कर मुक्त होगा जबकि पहले 50 फीसदी राशि ही कर मुक्त थी.
- लाभांश के रूप में मिलने वाली 3,000 रुपए की अतिरिक्त राशि कर मुक्त होगी.
- 50,000 रुपए से ज्यादा आय वालों के आयकर पर 5 फीसदी अधिभार एक साल और जारी रहेगा.

उद्योगों के लिए

- घरेलू इस्तेमाल में आने वाली बिजली के उपकरण, स्टेनलेस स्टील के बर्तन और खिलौनों पर उत्पाद कर उठा लिया गया है.
- ईंधन बचत वाली 1000 सीसी से अधिक क्षमता वाली कारों का उत्पाद कर 25 से बढ़ाकर 30 फीसदी कर दिया गया.
- कपड़ा उद्योग और गृह निर्माण सामग्रियों का उत्पादन करने वाले उद्योगों को उत्पाद कर में भारी रियायतें दी गई हैं.
- सीमेंट पर लगने वाला उत्पाद कर कम कर दिया गया है.

कंपनियों के लिए

- मजदूरों को भागीदारी देने वाली योजनाओं पर खर्च आयकर से मुक्त होगा.
- निर्यात से होने वाली आय कर मुक्त होगी जबकि अभी 50 फीसदी ही कर मुक्त है.
- उत्पाद कर पर 5 फीसदी सूखा राहत अधिभार जारी रहेगा. इसके साथ ही पांच फीसदी अतिरिक्त उपकर लगाया गया है.

शेयर बाजार के लिए

- उपक्रम पूंजी कोष से मिले पूंजीगत लाभ को कर मुक्त कर दिया जाएगा.
- नए शेयर/डिबेंचर में साझा कोषों द्वारा किए गए निवेश के लाभ को भी कर मुक्त कर दिया गया है.

ग्रामीणों के लिए

- फसल के लिए कर्ज पर ब्याज दर कम किए जाने से किसानों को लाभ होगा. बैंकों से कहा गया है कि वे खेती के लिए ज्यादा रकम दें. रासायनिक खाद कंपनियां माल पर 7.5 फीसदी की छूट देंगी.
- 1988 में 5 लाख ग्रामीण घरों को एक बत्ती दी जाएगी.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"किसानों की क्रय-शक्ति बढ़ने से उद्योग जगत को लाभ होगा"

हरीश महिंद्रा
अध्यक्ष
महिंद्रा यूजीन स्टील कंपनी

"हर आदमी खुश है क्योंकि बजट कठोर हो सकता था. इसी नजरिये से न देखा जाए"

विनोद दोषी
अध्यक्ष
प्रीमियर आटोमोबाइल

टेरकस, धुलाई के साबुन, खिलौनों, पेंसल छीलने वाली मशीन, बिजली के बल्ब और घरेलू उपकरण, स्टेनलेस स्टील के बर्तन, जग, कप और कटोरी वगैरह को सस्ता कर दिया. और हर बारीक चीज का ध्यान किस तरह रखा गया है, यह सिंदूर, काजल और महावर को कर मुक्त करने से स्पष्ट होता है.

साथ ही तिवारी ने अपनी समाजवादी शैली में ही कार और एअर कंडीशनर जैसी तथाकथित विलासिता की चीजों पर उत्पाद कर में वृद्धि कर दी है. संपत्ति कर देने वालों पर फिर से जायदाद कर लाद दिया गया है.

बजट आने के पहले वित्त सचिव एस. वेंकटरमनन ने कहा था कि तिवारी जी का बजट 'खास' होगा. जिस तरह की रियायतें वित्तमंत्री ने दीं, उस हिसाब से यह खास था भी. बजट के लक्ष्य पर हो रही आलोचना के जवाब में भी तिवारी ने कहा कि यह याद रखना चाहिए कि यह गरीब देश है. लेकिन उद्योग जगत के अनेक लोग इसे सस्ती लोकप्रियता बटोरने वाला बजट कह रहे हैं.

हां, शेयर बाजार के लोगों को इस बजट से जरूर निराशा हुई. उन्होंने ढेर सारी उम्मीदें लगा रखी थीं. और यह निराशा बजट के बाद बाजार में आई गिरावट से भी झलकती है. पर अधिकांश लोग खुश हैं कि चलो सस्ते में जान छूटी. पूरे व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए प्रीमियर आटोमोबाइल के अध्यक्ष विनोद दोषी कहते हैं, "हर आदमी खुश है क्योंकि बजट बहुत कठोर हो सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि बजट को सिर्फ इसी नजरिये से नहीं देखा जाना चाहिए."

यह बात सही भी है. जैसे सरकार ने गहराते वित्तीय संकट और कर्ज वाली समस्या दूर करने में हाथ लगाया हो ऐसा नहीं लगता. सरकार ने बजट के पहले की गई

रोजमर्रा की वस्तुएं: फायदेमंद छूट

मूल्य और करों की वृद्धि से 2000 करोड़ रुपए से काफी अधिक पैसा जुटा लिया जबकि बजट की कुल रियायतें 620 करोड़ रुपए की हैं. उसने अपना कर वाला जाल अधिक नहीं कसा. नए करों से सरकार को 615 करोड़ रुपए मिलेंगे और इससे अधिक राशि रेलवे ने अपने भाड़े में वृद्धि से ही पा ली है.

इसके बावजूद अधिकांश व्यापारी मानते हैं कि ग्रामीण इलाकों को दी गई रियायतों से किसानों के पास भी कुछ पैसा होगा और उपभोक्ता सामान और मशीनरी की मांग बढ़ेगी. उद्योगपति हरीश महिंद्रा कहते हैं, "किसानों की क्रय शक्ति बढ़ने से व्यापार-उद्योग जगत को लाभ होगा."

कृषि को दी गई रियायतें काफी अधिक हैं और सूखे वाले वर्ष में इसका मतलब भी समझ में आता है. कीटनाशक और खर-पतवारनाशक पर आयात शुल्क कम होगा, नई ग्रामीण ऋण नीति लागू की जाएगी और

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नारायणदत्त तिवारी

'यह चुनावी बजट नहीं है'

नारायणदत्त तिवारी शायद भारत के पहले वित्तमंत्री हैं जो समाजवादी रस में पगे हुए हैं. आजादी के पहले वे कांग्रेस समाजवादी दल में रहे. उनके बजट से उनकी समाजवाद में आस्था ही झलकती है. बजट पेश करने के कुछ दिन बाद ही कार्यकारी संपादक ***टी.एन. नाइनन*** *और प्रमुख संवाददाता* ***पलकुन्नथु जी. मथाई*** *ने उनके दफ्तर में उनसे बातचीत की. उसके कुछ प्रमुख अंश:*

● ***बजट बनाते समय आपने किन बुनियादी लक्ष्यों को ध्यान में रखा?***

आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए वार्षिक योजना के लिए पैसा तय करना, रक्षा के लिए पर्याप्त धन देना और किसानों खासकर छोटे किसानों को प्रमुखता देना. हमें खेती के लागत खर्च को कम करना था.

● ***ग्रामीण क्षेत्र को इस बार इतनी प्रमुखता क्यों दी गई?***

सूखे के कारण. कृषि अभी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है. हमारा सुरक्षित भंडार 2.3 करोड़ टन से घटकर 1.4 करोड़ टन के आसपास रह गया है. आगे की जरूरतों के लिए ज्यादा बड़ा भंडार होना चाहिए.

एक सर्वेक्षण के मुताबिक सिर्फ सात फीसदी लोगों का मानना है कि पैसा गरीब लोगों के पास गया है. आम धारणा है कि हम लोग अमीरों का, उद्योगों का अधिक ख्याल रखते हैं और कृषि को भूल गए हैं.

● ***तो आप इस गड़बड़ को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं?***

हम पहले भी इसे ही प्रमुखता देते थे.

● ***यह भी कहा जा रहा है कि यह चुनावी बजट है.***

अगर लोकोन्मुखी बजट भी बनाया जाए तो आलोचक इसे चुनावी बजट ही कहेंगे. इसमें हमारे चुनाव घोषणापत्र को लागू करने की कोशिश जरूर की गई है.

● ***आपने अलग तरीके से जायदाद शुल्क को वापस क्यों ला दिया है?***

सामाजिक न्याय के लिए इसे वापस लाया गया है.

● ***क्या लोकोन्मुखी बजट बनाने में घाटा बढ़ाकर सरकार ने अपनी वित्तीय स्थिति को खराब नहीं कर लिया है?***

जो लोग यह बात कहते हैं, उन्हें फिर से बजट पढ़ना चाहिए.

● ***ऐसा क्यों?***

इसलिए कि अधिकांश प्रस्ताव उत्पादन बढ़ाने वाले हैं. अगर कर्ज की सीमा नहीं बढ़ाई जाए तो किसान खाद कैसे खरीद सकेंगे? जलधारा योजना उत्पादक है. कुटीर ज्योति योजना झोपड़ीवालों के लिए है. सामान्य बीमा निगम पहले ही घरों का बीमा करता है. अब हम झोंपड़ियों को जलने से बचाने के लिए उन्हें इनका बीमा करने पर प्रीमियम देंगे. मैं झोंपड़ी में ही जन्मा-पला

हूं. क्या आपको लगता है कि गरीब आदमी खुद अपनी झोंपड़ी जला देगा?

● ***आपकी बात सही है. लेकिन आपने घाटे और खर्च को कम नहीं किया. राष्ट्रीय कर्ज एक बड़ी समस्या का रूप धारण कर चुका है. उस पर देनदारियां बढ़ रही हैं.***

यह घाटा सकल राष्ट्रीय उत्पादन का दो-ढाई फीसदी है. मैं मानता हूं कि हमें घाटे की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा नहीं देना चाहिए. लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था इस दो-ढाई फीसदी घाटे को पचाने में सक्षम है. हम इसका इस्तेमाल उत्पादक कामों में कर रहे हैं, न कि मुद्रास्फीति बढ़ाने वाले कामों में. जहां तक कर्ज की बात है, हम दूसरे देशों की अपेक्षा बहुत सावधान हैं.

● ***क्या घाटे से मुद्रास्फीति बढ़ेगी?***

अगर मानसून ठीक हुआ तो सारी गड़बड़ियां अपने आप दूर हो जाएंगी.

● ***अगर नहीं हुआ तो क्या होगा?***

फिर सोचना पड़ेगा. वैसे हमें तो यही उम्मीद है कि मानसून ठीक बरसेगा.

● ***लोग कहते हैं, यह नरम बजट है. आपने ऐसा बजट क्यों बनाया?***

लोग तो हर तरह की बात करते हैं. मैंने उत्तर प्रदेश के आठ बजट बनाए हैं और मुझे पता है कि आलोचना क्या होती है. अगर आप सावधान हैं तो आपको नरम कहा ही जाएगा. भारतीय परिस्थितियों में आप बहुत कठोर या बहुत नरम नहीं बन सकते. कठोर रहते हुए भी नरम होना है.

● ***खिलौना और सिंदूर जैसी चीजों का ध्यान रखने के कारण आपका बजट एकदम अलग तरह का है. पैसे के हिसाब से एकदम महत्वपूर्ण न होने वाली चीजों का भी ध्यान रखने का क्या कारण है?***

ये चीजें आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं. इसलिए मुझे लगा कि इन पर कर नहीं लगना चाहिए.

● ***आपके कहने का अर्थ है कि आपका बजट पूर्ववर्त्तियों से अधिक समाजवादी है?***

हमने यही संदेश देने की कोशिश की है. पर यह भारतीय समाजवाद का संदेश है. यह उसी दिशा में उठा कदम है. जीवन बीमा निगम का सामाजिक सुरक्षा कोष रिक्शावालों, कुली, दैनिक मजदूरी पर काम करने वालों के लिए है. अभी तक ऐसी कोई योजना नहीं थी. अगर हम उनके आंसू पोंछने की कोशिश करते हैं तो लोग कहते हैं कि यह तो डेफिसिट फाइनेंसिंग हो गया. हम सभी उसी पृष्ठभूमि में हैं और हमने गरीबी देखी है. और इस योजना पर बहुत पैसा भी नहीं खर्च होगा. हमने इस कोष के लिए 33 करोड़ रुपए ही दिए हैं. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की एक किस्त देने में 400 करोड़ रुपए निकल जाते हैं. हमने बहुत कुछ नहीं कर दिया है पर यह एक शुरुआत तो है ही

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बैंकों में कृषि क्षेत्र को 3000 करोड़ रुपए अधिक का कर्ज देने को कहा गया है. खाद की कीमत में 7.5 फीसदी कटौती हो गई है. अपने वित्त वर्ष में कृषि पर चालू वित्त वर्ष से 12 फीसदी अधिक पैसा खर्च होगा. लेकिन कृषि, ग्रामीण विकास, बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई वगैरह का कुल खर्च बजट के करीब 11 फीसदी ही बना हुआ है.

मोटे तौर पर देखें तो कुछ रियायतें तो दिखावटी भर लगती हैं जैसे खाद पर दी गई रियायत से मुश्किल ही होगी. कंपनियों के भंडार में 33 लाख टन खाद पड़ा है. दो साल पहले कंपनियों ने बिक्री बढ़ाने के ख्याल से प्रति टन 400 रुपए की रियायत दी थी. यह तरीका चला नहीं और सरकार ने पिछले साल इसे बंद कर दिया.

बजट से दूसरे लोग भी दुखी हैं. सरकार ने 1000 सीसी क्षमता से अधिक इंजन वाली ईंधन की बचत करने वाली कारों पर उत्पाद कर 25 से बढ़ाकर 30 फीसदी कर दिया है. मारुति पर इसका असर नहीं पड़ेगा. ऑटोमोबाइल निर्माता संघ के अध्यक्ष एस.एल. भट्टर कहते हैं, "यह बहुत गड़बड़ फैसला है और इससे सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति सरकार का अतिरिक्त स्नेह झलकता है."

कार वाले विवाद को छोड़ दें, तो बाकी उद्योगों के मामले में सरकार ने उदारता बरती है. कपड़ा, सीमेंट, अल्यूमिनियम और बिजली के उपकरण उद्योग को काफी लाभ मिला है. सिर्फ कपड़ा उद्योग को ही 267 करोड़ रुपए का लाभ होगा.

और भी महत्वपूर्ण फैसले हैं. जैसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का गठन जो तीन महीने के अंदर ही छोटे व्यापारियों को कर्ज देना शुरू कर देगा. निर्यातकों को काफी फायदा होगा क्योंकि निर्यात की उनकी पूरी कमाई कर मुक्त हो गई है. और नए नियमों के अनुसार जो लोग रद्दी माल, शराब या वन के उत्पादन बेचेंगे उन्हें ग्राहकों से कर वसूल कर सरकार के पास जमा कराना होगा.

आखिर में यह बात महत्वपूर्ण है कि बजट अपने सीधे और प्रमुख असर के लिए ही याद किए जाते हैं. चरण सिंह का 1979 का बजट भयंकर महंगाई लाने और विश्वनाथ प्रताप सिंह का 1985 का बजट कर नीति और शेयर बाजार में नाटकीय बदलाव के लिए याद किया जाता है. बजट के बारे में बड़ी बातें कही सुनी जाएंगी, पर तिवारी का बजट करों में मामूली रियायत के साथ अधिक-से-अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए पेश किया जाएगा. वैसे यह सरकार की वित्तीय स्थिति को और बिगाड़ने ही जा रहा है.

—पलकुन्नथु जी. मथाई

सरकारी वित्त

आंख फेर ली

अर्थशास्त्री जैसे-जैसे बजट के आंकड़ों को बारीकी से देख रहे हैं, वे एक खतरनाक निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं: सरकार ने वित्तीय गड़बड़ियां ठीक करने के लिए कोई खास कोशिश नहीं की है. दिल्ली के आर्थिक विकास संस्थान के प्रो. के. कृष्णमूर्ति कहते हैं, "मुद्दे बड़े साफ हैं, बढ़ता कर्ज बढ़ता घाटा, योजनाओं में निवेश के लिए संसाधनों की मुश्किल और सबसिड़ी. लेकिन बजट में इन पर ध्यान नहीं दिया गया है."

तिवारी के बजट में गरीबों के बारे में तो बड़े विस्तार से चर्चा की गई है पर वित्तीय समस्याओं के बारे में कम ही कहा गया है. तिवारी को खर्च और बर्बादी घटाने और अधिक संसाधन जुटाने की कोशिश करनी चाहिए थी.

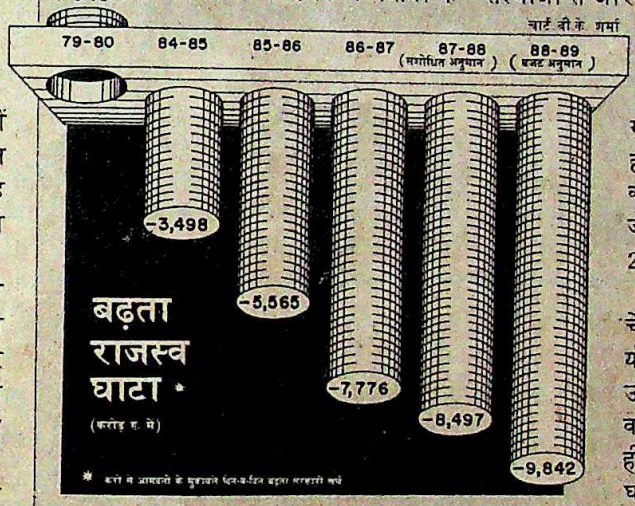

सरकार प्रशासन चलाने (राजस्व खर्च) जैसे गैर-विकासात्मक मदों में तो ज्यादा खर्च कर रही है पर उत्पादक संपत्तियां (पूंजीगत खर्च) बनाने पर उसका ध्यान कम जा रहा है. 1984-85 के बाद से राजस्व खर्च तो दूना हो गया है, पर पूंजीगत खर्च में इसके आधे दर पर भी वृद्धि नहीं हुई.

विवेकपूर्ण ढंग से बजट बनाने के लिए जरूरी है कि रोज-ब-रोज का खर्च कर-राजस्व से ही चलना चाहिए और अतिरिक्त राजस्व को पूंजीगत निवेश में लगना चाहिए. लेकिन इस दशक के अधिकांश समय उलटा ही हुआ है. सरकार कर्मचारियों का वेतन चुकाने के लिए भी उधार लेती रही है. परिणाम है राजस्व घाटे में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि (चार्ट देखें).

और भी कई बातों से सरकारी अविवेक झलकता है. कर-राजस्व में वृद्धि की दर पिछले पांच वर्षों में 19 फीसदी से घटकर 12.26 फीसदी रह गई है. राजस्व घाटे के बढ़ते जाने का एक कारण यह भी है. इस बीच पूंजीगत संपत्ति बनाने पर लगने वाली राशि में वृद्धि दर चार वर्षों के अंदर ही 18 फीसदी से घटकर मात्र 7 फीसदी रह गई है.

और इन सब गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ता है. सरकार ने सूद की दर बढ़ते जाने के बावजूद लोगों और वित्तीय संस्थाओं से और अधिक कर्ज लेने का क्रम जारी रखा है. सूद की देनदारियां बढ़ते जाने से देश मुश्किल में फंस गया है. सूद की देनदारियां ही अब सालाना 14100 करोड़ रुपए को छू लेंगी जो एक साल के बजट का 23 फीसदी होता है.

अर्थशास्त्री भी अब चेतावनी देने लगे हैं. योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डी.टी. लकड़ावाला कहते हैं, "अब एक ही रास्ता बचा है कि खर्च घटाया जाए और जो पैसा खर्च हो रहा है उसको अधिक उपयोगी बनाया जाए. बजट में ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं दिखती." उनकी बात सही है. जैसे इस बर्ष सरकार की समस्त प्राप्तियों का 51 फीसदी तो प्रतिरक्षा, सूद और सबसिडी देने पर ही खर्च होगा.

सरकार ने अपने राजस्व में मात्र 615 करोड़ रुपए की वृद्धि का प्रस्ताव रखा है. यह और भी परेशानी पैदा करेगा. बजट का घाटा इतना बढ़ गया है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर आर.एम. मल्होत्रा को चेतावनी देनी पड़ी कि इससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी.

लेकिन सरकार घाटे से चिंतित नहीं है. तिवारी का तर्क है कि घाटा सकल राष्ट्रीय उत्पादन का मात्र ढाई फीसदी ही है. यह कहने के बाद भले ही वे आत्म-संतुष्ट लगें पर उन्होंने बुनियादी समस्याओं को अभी पर्दे की ओट में कर दिया है. अंततः इसकी महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी.

—पलकुन्नथु जी. मथाई

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शेयर बाजार

उम्मीदों पर पानी

बजट से कुछ हासिल न हुआ

शेयर बाजार पर पिछले साल के बजट का कोई खास असर नहीं रहा और इस बार का बजट भी कोई अलग नहीं है. नारायणदत्त तिवारी की छोटी-मोटी तब्दीलियों से कोई भी खुश नहीं लगता.

निवेश पर मिलने वाले लाभांश पर कर संबंधी जो रियायत दी गई, उससे कोई ज्यादा उत्साह नहीं दिखता. पोलिएस्टर धागों और रेशों पर दी गई भारी रियायत का भी बाजार पर असर पड़ता नजर नहीं आता क्योंकि पिछले एक पखवाड़े में ही रिलायंस के शेयर 14 रुपए गिर गए हैं. इसी तरह सीमेंट पर भी मामूली रियायत मिली पर एससीसी के शेयर गिर गए. रासायनिक खाद कंपनियों की हालत भी बेहतर नहीं रही. सदर्न पेट्रोकेमिकल्स और गुजरात फर्टिलाइजर दोनों की ही हालत खराब रही. हो सकता है कि साझा कोषों के लिए दी

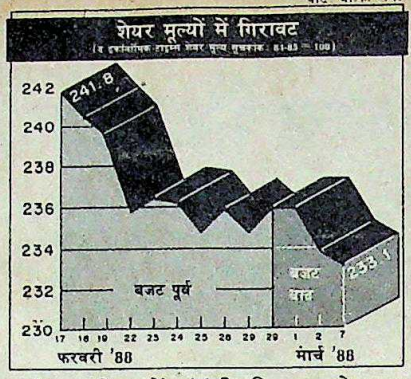

जाने वाली करों संबंधी रियायत से कुछ फायदा हो और उधर अधिक पूंजी जाए. पर अभी बाजार में अनिश्चितता ही है.

प्रमुख व्यवसायियों का मानना है कि बजट में ग्रामीण क्षेत्र को जो फायदे पहुंचाए गए हैं उनसे मांग बढ़ेगी और आर्थिक विकास की प्रक्रिया तेज होगी. करों का बोझ काफी बढ़ने का अंदेशा था. ऐसा नहीं होने से बड़े व्यापारी जरूर राहत महसूस करते होंगे.

और ऐसे में इकॉनॉमिक टाइम्स शेयर मूल्य सूचकांक का फरवरी के मध्य के 241.8 प्वाइंट से गिरकर बजट के एक हफ्ते बाद 233.1 पर पहुंच जाना स्वाभाविक ही है. बजट आने के बाद बाजार में कुछ समय के लिए जान लौटती जरूर लगी थी. ऐसा कई महीनों से लागू प्रतिबंधों के उठने की आशा से हुआ था.

जल्दी ही कंट्रोल वाले मुद्दे बजट से भी प्रमुख हो गए और व्यापार जगत से यह धमकी मिलने लगी कि अगर कंट्रोल नहीं हटा तो हड़ताल होगी. अगर सरकार दवे आयोग की रिपोर्ट के दूसरे चरण को लागू करती है तो इसका मतलब होगा कि वह भी मानती है बाजार से कंट्रोल हटाना आज की हालत को ठीक करने में मददगार होगा. लेकिन ऐसा होगा ही यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी तक वित्तीय संस्थानों को यह मुश्किल रही है कि जब भी कीमतें थोड़ी बढ़ जाती हैं और वे अपने शेयर उतारती हैं तो कोई खरीदार नहीं मिलता. छोटे निवेशक अभी शेयर बाजार का रुख करने के पक्ष में नहीं हैं.

अगर बजट के बारे में शेयर बाजार की प्रतिक्रिया कोई उत्साहजनक नहीं रही है तो वित्तमंत्री भी बाजार की मांगों के प्रति उदासीन हैं. सरकार की मुख्य चिंता अभी सूखे और दूसरी आर्थिक मुश्किलों से निबटने की है. ऐसे में शेयर बाजार को अपनी मुश्किलों का सामना खुद ही करना होगा.

जमा स्टॉक

	1988 ऊंचा	नीचा	बंद 7.3.88	पखवाड़े में स्टॉक की स्थिति
अशोक लेलैंड	36.50	30.50	32.00	1.00 +
एसोसिएटेड सीमेंट	180.00	137.00	140.00	17.50 —
एटलस कोप्को	63.50	40.00	40.00	5.00 —
एशियन पेंट्स	169.00	140.00	148.75	2.50 —
बजाज ऑटो	520.00	383.00	415.00	11.25 +
बड़ौदा रेयॉन	168.00	140.00	160.00	5.00 +
बाटा इंडिया	71.50	57.50	58.50	3.25 —
बेयर	320.00	280.00	290.00	10.00 —
भारत फोर्ज	121.00	101.00	119.00	8.00 +
बिरला जूट	44.00	36.50	38.00	1.00 +
ब्लो प्लास्ट	125.00	45.00	54.50	5.50 +
बॉम्बे डाइंग	135.00	94.00	123.50	1.50 —
बुक बांड	87.00	75.00	78.75	1.25 +
ब्रिटानिया इंडिया	109.00	84.00	89.50	0.50 +
सीएट टायर्स	88.00	75.00	81.25	4.75 —
सेंचुरी एंका	1440.00	1080.00	1425.00	165.00 +
क्लोराइड इंडिया	80.50	69.00	71.00	1.50 —
सिंतुरगिया	74.00	61.00	66.00	1.00 —
कोलगेट	220.00	186.25	192.50	2.50 —
डीसीएम	38.25	29.00	29.50	—
डनलप	83.00	71.00	74.25	0.25 +
एस्कार्ट्स	44.00	39.00	39.00	0.50 —
फिनोलेक्स केबिल्स	380.00	300.00	315.00	3.00 —
फूड स्पेशिलिटीज	142.00	106.25	106.25	10.75 —
गरवारे नाइलोन	30.00	20.00	30.00	6.50 +
जी.ई. शिपिंग	26.35	20.50	22.85	1.90 —
गुजरात स्टेट फर्टि.	118.00	86.50	99.00	4.00 —
ग्रासिम इंडिया	104.75	83.50	85.50	3.00 —
हिंदु. एल्यूमिनियम	139.00	116.00	121.00	2.00 —
हिंदुस्तान कोकोआ	215.00	72.50	80.00	5.00 —
हिंदुस्तान लीवर	81.00	65.00	67.00	1.50 —
हिंदुस्तान मोटर्स	25.00	17.30	17.90	2.30 —
हिंदुस्तान डॉर	212.50	140.00	148.75	21.25 —
आई.ई.एल	43.75	36.25	37.50	0.25 —
इंडियन होटल्स	120.50	100.00	102.50	0.50 —
इंडियन आर्गेनिक	23.00	17.00	17.50	1.00 —
इंडियन रेयॉन	58.00	46.00	49.00	—
इंडाल	223.75	162.50	166.25	10.00 —
इंगरसॉल-रैंड	335.00	262.50	262.50	20.00 —
आई.टी.सी.	39.75	30.00	32.00	1.00 —
जे.के. सिंथेटिक्स	69.00	48.00	55.00	2.50 +
काइनेटिक इंजी.	185.00	161.25	175.00	5.00 +
किर्लोस्कर क्युमिस	57.50	48.00	57.50	6.00 +
केएसबी पम्प	425.00	310.00	320.00	50.00 —
लारसन-टुब्रो	95.50	75.50	78.00	3.50 —
लिप्टन	67.00	52.00	56.00	1.50 +
लोहिया-मशीन्स	13.50	9.00	10.00	0.75 +
महिंद्रा-महिंद्रा	63.00	51.50	55.00	1.00 —
मेक्डोवेल	83.50	72.00	72.00	4.00 —
मोटर इंडस्ट्रीज	587.50	490.00	505.00	20.00 —
मुकुंद आयरन	85.00	72.50	78.50	2.50 +
नेशनल आर्गेनिक	525.00	420.00	425.50	19.50 —
निरलॉन	8.75	5.00	7.00	0.50 +
ओरके सिल्क मिल्स	30.00	17.50	21.50	1.00 +
पेइको इलेक्ट्रॉनिक्स	33.75	26.00	27.50	—
ओसवाल आग्रो	134.50	82.00	86.62	8.88 —
ओटिस एलिवेटर	215.00	185.00	185.00	12.50 —
प्रीमियर ऑटो	31.00	23.00	25.00	2.00 —
रैनबेक्सी	102.50	78.00	79.00	3.00 +
रेमंड	96.00	44.00	47.50	0.50 +
शॉ वैलेस	132.00	57.00	59.00	—
रिलायंस इंडस्ट्रीज	117.00	82.00	82.00	14.00 —
रिचर्डसन हिंद	305.00	260.00	277.50	5.00 +
श्रीराम फाइबर्स	42.75	32.50	34.50	0.50 —
एसकेएफ बैयरिंग	1315.00	1058.00	1240.00	20.00 —
सीमेन्स इंडिया	80.00	65.00	65.00	4.00 —
स्पिक	37.00	27.25	27.25	4.00 —
टाटा स्टील	685.00	568.75	593.75	6.25 —
टेल्को	400.00	340.00	345.00	15.00 —
विम्को	24.00	18.00	20.00	0.50 +

भारतीय रुपए का मूल्य

देश	मुद्रा	इकाई	मुद्रा की खरीद (रुपए में)	मुद्रा की बिक्री (रुपए में)
आस्ट्रेलिया	डालर	1	9.5621	9.4687
आस्ट्रिया	शिलिंग	1	1.1094	1.0875
बहरीन	दीनार	1	34.7913	34.7190
बांग्लादेश	टका	100	42.2119	42.1613
कनाडा	डालर	1	10.4865	10.3827
डेनमार्क	क्रोनर	1	2.0383	2.0166
मिस्र	पौंड	1	9.3120	9.2519
फ्रांस	फ्रैंक	1	2.3391	2.2805
हांगकांग	डालर	1	1.7084	1.6910
इंडोनेशिया	रुपिया	100	0.0790	0.0780
ईरान	रियाल	100	19.1410	19.1312
इटली	लीरा	100	1.0530	1.0103
जापान	येन	100	10.30	10.05
केन्या	शिलिंग	1	0.7532	0.7081
कुवैत	दीनार	1	47.3710	47.2120
मलेशिया	डालर	1	5.1116	5.0572
मारीशस	रुपया	1	1.0218	1.0000
नेपाल	रुपया	1	0.6232	0.5819
हालैंड	गिल्डर	1	6.9377	6.8454
पाकिस्तान	रुपया	1	0.7620	0.7013
सिंगापुर	डालर	1	6.6330	6.4580
स्पेन	पेसो	1	0.1143	0.1010
श्रीलंका	रुपया	1	0.4132	0.3992
स्वीडन	क्रोनर	1	2.1947	2.1713
स्विट्जरलैंड	स्विस फ्रैंक	1	9.4116	9.3128
तंजानिया	शिलिंग	1	0.1532	0.1491
थाईलैंड	बहत	100	51.8230	50.0000
ब्रिटेन	पौंड	1	23.2750	23.1426
सं. राज्य अमेरिका	डालर	1	13.1575	13.0275
सं. अरब अमीरात	दिरहाम	1	3.5820	3.5082
सोवियत संघ	रूबल	1	21.6220	21.5532
पश्चिम जर्मनी	जर्मन मार्क	1	7.9113	7.7198

स्रोत—बैंक ऑफ टोक्यो, नई दिल्ली, 8.3.88

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar and eGangotri

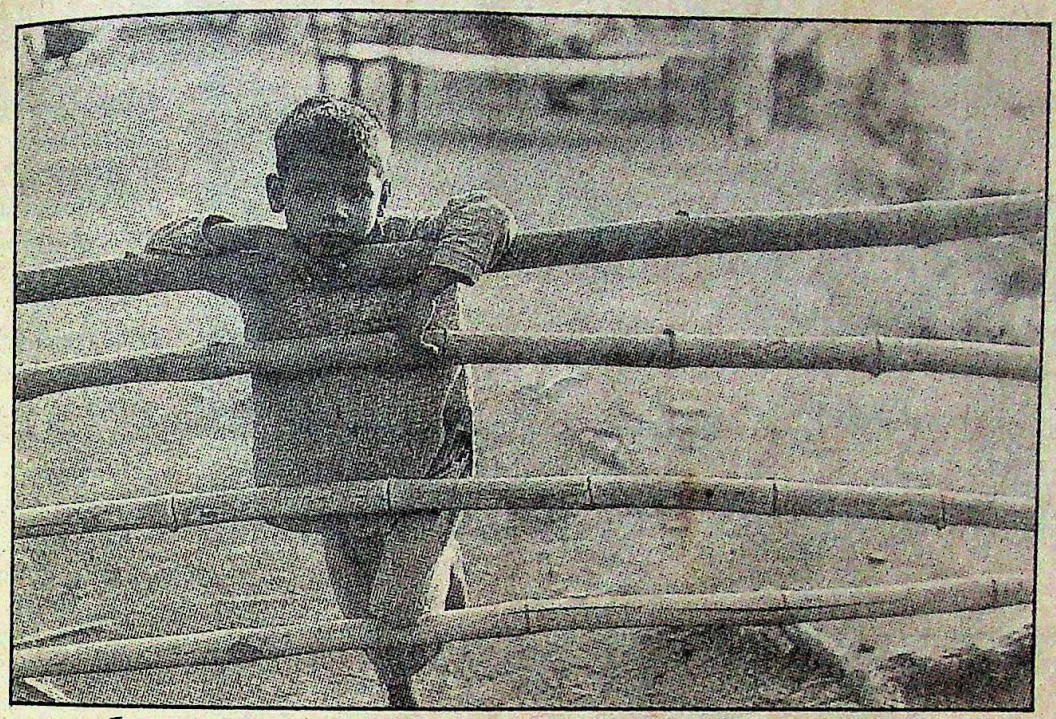

6 साल की उम्र में ही यह बच्चा जीवन की लड़ाई में उतर गया है। छिन गया है इससे इसका बचपन। कारण है हम और आप। क्योंकि हम और आप मिल कर करते हैं उस पैसे की बरबादी जिससे इसके जैसे 10 करोड़ बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाया-लिखाया जा सकता है।

दुख की बात तो यह है कि इतना बड़ा सच हमें छूता तक नहीं। कहीं चुभता भी नहीं। क्योंकि हमारे पास कई ज़रूरी चीज़ें हैं सोचने को-करने को। ऐसी फ़ालतू बातों के लिए भला समय कहाँ? हमारी आँखों पर-बंधी लापरवाही की पट्टी हमें कुछ देखने नहीं देती।

2000 करोड़ रु० की बरबादी हर साल हो रही है और यह हम सब मिलकर कर रहे हैं।

सड़कों पर, रसोई-घरों में, कारखानों और खेतों में। हर जगह, हर कहीं होती है पेट्रोलियम की बरबादी। क्योंकि ज़्यादा ईंधन खाने वाले पुराने डिज़ाइन के उपकरण उपयोग में लाये जाते हैं। सवारी की सही देखभाल नहीं होती। और न ही हमारी आदतों और ड्राईविंग के तरीकों में सुधार।

आपके ज़रा से जागरुक प्रयास से इस फ़ज़ूलखर्ची को रोका जा सकता है। लोगों की सोई हुई चेतना को जगाया जा सकता है। बिखरी हुई आवाज़ों को इकट्ठा किया जा सकता है। बहुत बरबादी हो चुकी। अब और नहीं। आइए, अब इसके खिलाफ़ आवाज़ उठायें। अपने अखबारों में लिखें। अपनी कॉलोनी, ऑफिस, क्लबों, संस्थाओं – हर तरफ चर्चा करें। काम करने वाले लोगों की सक्रिय टोलियाँ बनायें।

आपकी मदद के बिना कुछ नहीं हो पायेगा। पेट्रोलियम बचाने का संदेश घर-घर तक आपको ही पहुँचाना है।

हम आशा करते हैं कि आप चुप रहने वाली भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे।
क्योंकि आप उन लोगों में से नहीं हैं जो इस पन्ने को पलट कर कहेंगे– **"मेरी बला से!"**

इस विषय पर आइए हमसे मिलिए। आपके विचारों का स्वागत है।

पेट्रोलियम कंज़र्वेशन रिसर्च एसोसिएशन
1008, नई दिल्ली हाऊस, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली-110 001 फोन: 3310006, 3319066

HTA 5371HIN

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रभात गंजियार

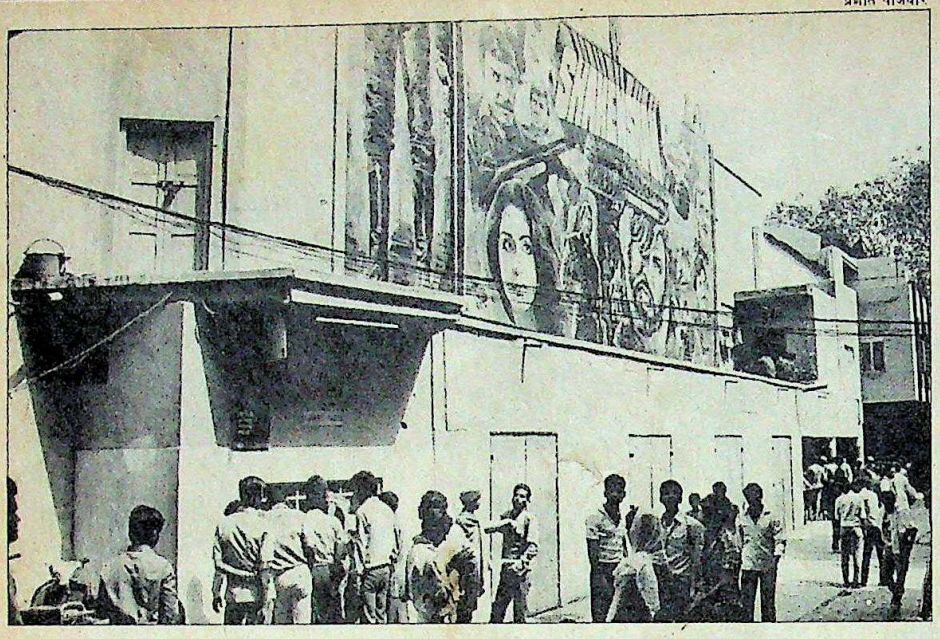

शहंशाह

फीकी और सुस्त सवारी

पहले हफ्ते तो दर्शक आए पर बाद में भीड़ घटती गई

अब जबकि अमिताभ बच्चन की बहु-प्रतीक्षित और बहुचर्चित फिल्म 'शहंशाह' देश भर के सिनेमाघरों में चौथे सप्ताह में प्रवेश कर रही है, एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है. क्या इसे एक हिट फिल्म कहा जा सकता है? यह बहस का मुद्दा हो सकता है लेकिन एक बात तय है कि इस फिल्म ने फिल्म उद्योग को दो धड़ों में बांटकर रख दिया है. एक तरफ वे लोग हैं, जो इसे हिट मानते हैं, दूसरे वे, जो इसे फ्लॉप बताते हैं. समर्थकों ने पत्रिकाओं में विज्ञापन देकर फिल्म की 'अभूतपूर्व सफलता' के दावे किए, वहीं बाकी लोगों ने इसे फ्लाप फिल्म बताकर दरकिनार कर दिया. सचाई इन दोनों के बीच कहीं है.

'शहंशाह' ने पहले हफ्ते तो देश भर में 'हाउस फुल' लिया, जो दूसरे हफ्ते भी जारी रहा. लेकिन तीसरे हफ्ते दर्शकों की भीड़ घटने के कारण टिकटों की बिक्री में भारी कमी आ गई. तीसरे हफ्ते बंबई क्षेत्र में सबसे ज्यादा—80 प्रतिशत दर्शक आए, कलकत्ता में तो संभावित बिक्री का केवल 49 प्रतिशत अर्जित किया जा सका.

लेकिन अमिताभ के समर्थकों का कहना है कि फिल्म ने हर वितरण क्षेत्र में रिकार्ड कमाई की है. फिर यह पहली फिल्म है, जिसे देश में उपलब्ध सभी केंद्रों पर रिलीज किया गया है. यह सब इस फिल्म से जुड़ी उत्सुकता को शांत करने के लिए किया गया था— पिछले 20 महीनों में यह अमिताभ की पहली फिल्म आई है. इस फिल्म के 50,000 रुपए लागत वाले 57 प्रिंट वितरित किए गए. हर प्रिंट के रिलीज पर 28.5 लाख रुपए का खर्च बैठा. फिल्मोद्योग के विश्लेषकों का अनुमान है कि 'शहंशाह' ने केवल बंबई में ही दूसरे हफ्ते के बाद 65 लाख रुपए वसूले हैं.

'शहंशाह' की तुलना अमिताभ की पहले की सफल फिल्मों 'दीवार' आदि से भी नहीं की जा सकती. आज के वीडियो युग से पहले गोल्डन जुबली मनाने वाली फिल्मों को हिट माना जाता था. लेकिन अब फिल्म की सफलता के मानदंड बदल गए हैं. यह सब हिंदी फिल्मोद्योग के ढांचे में बदलाव के कारण हुआ है. देश में बनने वाली कुल फिल्मों में हिंदी फिल्मों का अनुपात भी कम हो गया है. 1947 में जहां 50 प्रतिशत फिल्में हिंदी की हुआ करती थीं, पिछले साल यह संख्या घटकर 20 प्रतिशत रह गई. फिर भारत में सिनेमाघरों की वृद्धि की दर भी धीमी है—हर साल केवल चार प्रतिशत. सबसे बढ़कर, वीडियो के आने से

सिनेमाघरों पर दर्शकों की घटती भीड़: क्षणिक आकर्षण

परंपरागत शहरी दर्शक वर्ग सिनेमा हॉलों से मुंह मोड़ता जा रहा है. इसके अलावा फिल्म के निर्माण, वितरण और प्रदर्शन की लागत में तो बहुत वृद्धि हो गई है, लेकिन टिकटों की कीमतें उस अनुपात में नहीं बढ़ीं.

इन तथ्यों के मद्देनजर 'शहंशाह' को रिलीज करना फिल्म उद्योग की मजबूरी बन गई थी. फिल्म निर्माताओं और वितरकों के लिए जहां नतीजे उत्साहवर्द्धक रहे, प्रदर्शकों के लिए जोखिम ही बना रहा. फिल्मोद्योग के लोगों का कहना है कि प्रदर्शकों को फायदे की कोई उम्मीद तभी हो सकती है, जब फिल्म कम-से-कम आठ हफ्ते तक चले. लेकिन कानूनी या गैरकानूनी तरीके से वीडियो कैसेट की उपलब्धि और देश भर में फिल्म के एक साथ रिलीज होने में यह संभावना बहुत कम हो गई है.

मिसाल के तौर पर नागपुर में जहां नई फिल्म आम तौर पर दो सिनेमाघरों में रिलीज की जाती है—'शहंशाह' छह सिनेमाघरों में रिलीज की गई. फिल्म निर्माता अमित खन्ना कहते हैं, "ऐसा करने से आप जल्दी ही दर्शकों से हाथ धो बैठते हैं." फिर थिएटरों के ज्यादा किराए वाले महानगरों में दिखाए जाने वाले फिल्म प्रिंटों को वितरक अब कस्बाई क्षेत्रों में भेज रहे हैं. इसकी वजह साफ है. दिल्ली जैसे महानगर में टिकटों की बिक्री का 75 फीसदी किराए में ही निकल जाता है जबकि मुरादाबाद और हापुड़ जैसे अधिकांश छोटे शहरों में यह दर आधी होने के कारण मुनाफा भी ज्यादा ही मिलता है.

लेकिन 'शहंशाह' हिट है या फ्लॉप इस बहस में उलझने के कारण एक महत्वपूर्ण मुद्दा छूट गया है. जैसा कि खन्ना कहते हैं, "शहंशाह ने इस तथ्य पर मुहर लगा दी है कि फिल्मोद्योग संकट में है." यही बात पूरे उद्योग की प्रतिक्रिया में दिखाई देती है.

'शहंशाह' को लेकर चले विवाद से कुछ नसीहतें भी मिली हैं. अमिताभ बच्चन दर्शकों को तभी खींच सकते हैं जब फिल्म में भी कुछ दम हो. लेकिन एक बात तय है कि 'शहंशाह' ने फिल्मोद्योग में कोई बहुत जान नहीं फूंकी है. आखिर 'शहंशाहों' का ही तो तख्ता पलटा जाता है.

—सलिल त्रिपाठी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

...ion Chennai and eGangotri

ट्रेन्डी इरा

ग्रेविरा

ग्रेविरा सूटिंग्स

ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज लि. का एक उत्कृष्ट उत्पादन.

Kanishma/BTM/38/2720 HI

...main. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पश्चिम बंगाल

हाथियों को साधने की कठिन साधना

विशालकाय जानवरों का झुंड औरत ने काबू किया

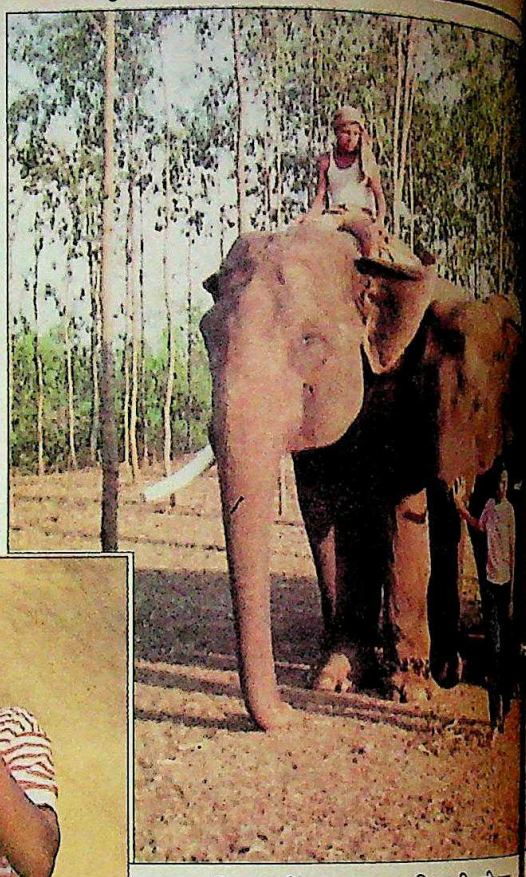

पार्बती बरुआ हाथियों के बीच ही पली-बढ़ी हैं. वह अपने इन दोस्तों से घंटों बतियाती रहती हैं

चौंतीस वर्षीया पार्बती बरुआ के सामने पहाड़ जैसी चुनौती थी. उन्हें करीब 50 मोटी खाल वाले जानवरों के झुंड को रास्ते पर लाना था. भटक जाने के कारण इन हाथियों ने पश्चिम बंगाल में मिदनापुर जिले के गांव में मानो चढ़ाई करके तबाही मचा दी और (अनजाने में) तीन आदमियों की जान भी ले ली. ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी बेबस थे. हताश होकर राज्य सरकार ने पार्बती को बुला भेजा. असंभव काम कर दिखाने वाली वे शायद हाथियों की एकमात्र महिला 'फंदी' (प्रशिक्षक) हैं.

पार्बती का हाथियों से पाला कोई पहली बार नहीं पड़ा है. सदियों से हाथियों से जूझते एक जमींदार घराने में पैदा होकर वे इन्हीं के बीच पली-बढ़ीं. पर उन पर अंकुश लगाना पार्बती के लिए भी टेढ़ी खीर थी. हाथियों के लिए जगह अनजान थी और वे अपनी नाराजगी स्थानीय लोगों पर उतार रहे थे.

बहादुर महिला ने अपने चार कुमकी (प्रशिक्षित हाथी), चार महावतों और चार 'पत्तावालों' (चारा इकट्ठा करने वालों) की मदद से इन बिगड़ैल जानवरों को रास्ता दिखाने का काम शुरू किया और पिछला पखवाड़ा बीतते-बीतते आखिर उन्हें काबू में कर ही लिया. भटके हुए जानवर सही रास्ते पर आगे बढ़ गए.

हर साल की तरह ये हाथी दिसंबर के शुरू में चारे की तलाश में बिहार के दलमा जंगल से निकल पड़े थे. घूमते-घूमते वे बंगाल में बांकुड़ा जिले में पहुंच गए. यहां वे हर बार आसपास के गांवों में धान की फसल को चट करते और हंड़िया (स्थानीय शराब) पी जाते. इसके बाद वे अमूमन दलमा की ओर लौट आते. पर हर साल उनके आने से तंग आ चुके ग्रामीणों ने हाथियों को सबक सिखाने का फैसला कर लिया. झांझ-मंजीरों, लाठियों-बल्लम और ढोलकों की मदद से उन्होंने इन अनचाहे मेहमानों को भगाने की कोशिश की. हाथियों ने उलटे भीड़ पर हमला कर दिया जिससे डरकर लोग भाग खड़े हुए. पर जल्दी ही गांववालों ने फिर से जुटकर हाथियों को भागने पर मजबूर कर दिया.

इस तरह समस्या की शुरुआत हुई. घबड़ाए हुए हाथी रास्ता भूल गए. जंगल में पहुंचने के चक्कर में वे पूर्व दिशा में कांसबती नदी की ओर बढ़ गए. नौ फुट लंबे एक नर हाथी की अगुआई में वे जंगल के एक टुकड़े से दूसरे की ओर बढ़ते गए. 40 किमी का रास्ता तय करने के बाद वे कांसबती नदी पार करके मिदनापुर पहुंचे. वन संरक्षक (पश्चिम क्षेत्र) एस. पालित कहते हैं, "उन्होंने 400 किमी का रास्ता तय किया ही होगा."

पर वक्त गुजरता गया. जाड़ा बीतने के साथ ही साल और यूकलिप्टस के वनों में चारा खत्म हो गया. सबसे बड़ी समस्या यह आई कि कुछ हथिनियां गर्भवती हो गईं. हाथियों को वहां तब तक रुकना पड़ गया जब तक नवजात हाथी चलने लायक नहीं हो गए.

चारे की समस्या और गंभीर हो गई और आखिर हाथियों ने गांवों पर कहर ढाना शुरू कर दिया. जिला वन अधिकारी डी.एन. शुक्ल कहते हैं, "उन्होंने धान की कटी फसल और हंड़िया पीने के लिए गांवों पर हमला बोल दिया था." दुर्घटनावश तीन ग्रामीण भी उन्होंने मार डाले. एक व्यक्ति की मौत तो दीवार गिरने से उस समय हुई जब एक हाथी एक संकरी जगह से निकलने की कोशिश कर रहा था. शराब के नशे में दो व्यक्ति तो हाथियों की तरफ ही भाग लिए और उन्होंने उन हाथियों पर सवारी करने की कोशिश की. एक चश्मदीद के अनुसार, "एक व्यक्ति तो यह चिल्लाता हुआ मरा कि मैं हाथियों का राजा हूं."

इस दौरान वन अधिकारी घबड़ाए रहे. जितना वे उन्हें खदेड़ने के प्रयास करते हाथी उतने ही परेशान हो उठते. सरकार ने पार्बती बरुआ को बुलाने का फैसला किया. वे वन संबंधी कार्यों के लिए सरकार को अपने हाथी किराए पर देती रही हैं.

वे दार्जिलिंग जिले के बामोनपोकरी गांव से अपने चार प्रशिक्षित हाथियों—गोपाल (30), लक्ष्मीमाला (22), लक्ष्मी प्रसाद (32) और राजू (15) के साथ मिदनापुर पहुंचीं. इलाका परिचित न होने से पार्बती को दार्जिलिंग के जिला वन अधिकारी सुबल ढौंडियाल पर निर्भर रहना पड़ा. दोनों ही हाथियों के विशेषज्ञ और पश्चिम बंगाल वन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सभी फोटो: कल्याण चक्रवर्ती

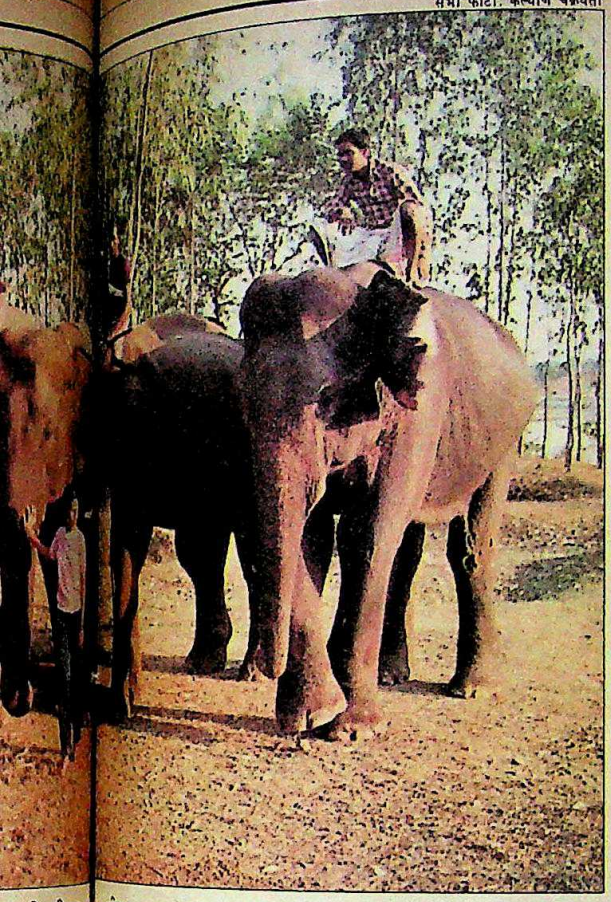

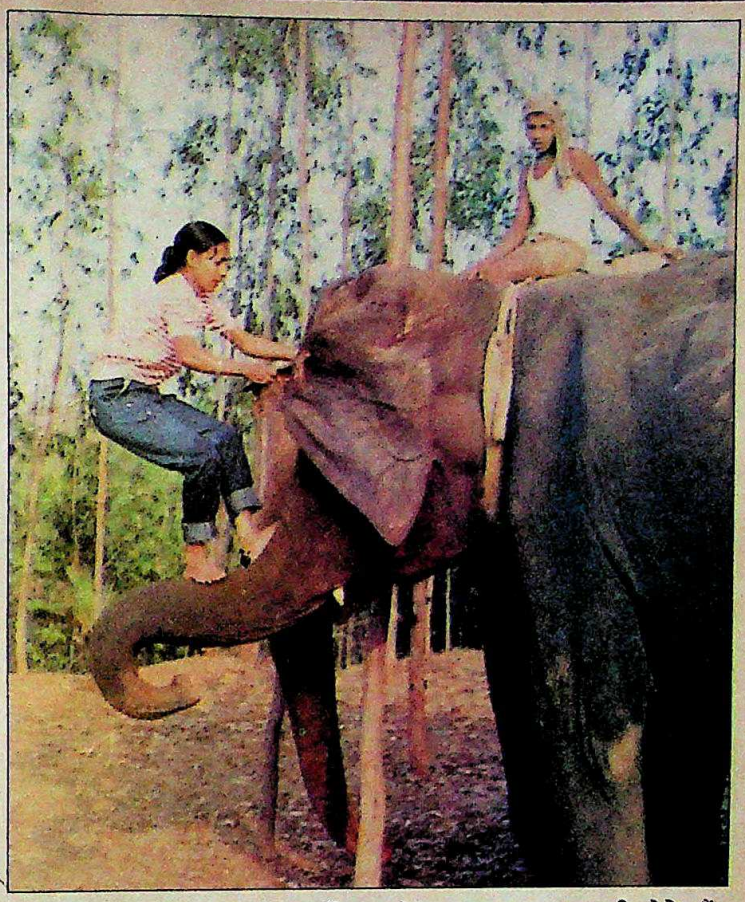

वीदन सलाहकार बोर्ड के सदस्य डी.के. जाहिड़ी चौधरी के साथ मिलकर 'ऑपरेशन खेदा' की योजना तैयार की.

तय हुआ कि मटगोधा के जंगल तक हाथियों पर दबाव बनाए रखा जाए. वहां से वे दलमा पहुंच सकते हैं. पर मुश्किल यह थी कि मटगोधा पहुंचने के लिए हाथियों को 30 किमी का करीब बंजर इलाका पार करना था. यहां पहुंचकर वे फिर लौट सकते थे. तीन बार पार्बती और उनके सहयोगियों ने हाथियों को कांसबती नदी के पार धकियाया पर टीम के हटते ही वे फिर लौट आते. फिर सोचा गया कि पीछा लगातार जारी रखा जाए. ज्यों ही पार्बती ने हाथियों को कांसवती के पार धकेला, त्यों ही नींद की गोलियों वाली बंदूकों, तेज रोशनी, नगाड़ों और पटाखों से लैस वन विभाग के कर्मचारियों ने मोर्चा संभाल लिया. हाथियों का झुंड फिर न भटक जाए, इसके लिए कई जगह बिजली के तार बांधे गए. यह रणनीति कारगर सिद्ध हुई और हाथियों का झुंड आखिर बांकुड़ा वन में पहुंच गया. लेकिन निगरानी तभी खत्म होगी जब तक बिन बुलाए मेहमान राज्य की सीमा पार कर बिहार नहीं पहुंच जाते.

इसी बीच पार्वती चर्चा का केंद्र बन गई हैं. उनके तंबू में कलकत्ता और विश्व भर के संवाददाताओं की भीड़ लगी रहती है. कलकत्ता के एक वृत्तचित्र निर्माता ने तो उन पर फिल्म बनाने की भी सोच ली है. सालबोनी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मृग वन स्थित अपनी छोलदारी में रैंगलर जींस व टी-शर्ट पहने और कंधे पर दुनाली बंदूक लटकाए पार्बती खुद की अपेक्षा अपने हाथियों के बारे में बताने को ज्यादा उत्सुक हैं. उनका कहना है कि अपने जानवरों से दूर रहने के बजाय वे मर जाना पसंद करेंगी.

पार्बती कहती हैं, "हाथियों से रिश्ता तो मुझे विरासत में मिला है." वे अपने इन दोस्तों से घंटों बतियाती रहती हैं. वे कहती हैं, "हम आंखों ही आंखों में बात करते हैं. वे मुझसे स्नेह करते हैं क्योंकि मैं उनकी भावनाओं का ख्याल रखती हूं. मेरी एक आवाज पर वे दौड़ते हुए आ जाते हैं." उनके दैनिक कार्यक्रम में अपने इन साथियों को नहलाना, जंगल में घुमाना और प्रशिक्षण देना शामिल है. पार्बती का विवाह '1970 के मध्य में कभी' एक बैंक कर्मचारी पुलिन दास से हुआ था. पर उनकी ज्यादा दिनों तक नहीं निभ पाई.

इस सदी के शुरू में सरकार द्वारा शिकार पर प्रतिबंध लगाने से पहले उनका परिवार हाथियों को पकड़कर बेचा करता था. बरुआ परिवार ने लगभग 1,029 हाथी बेचे हैं. भूटान, कूच बिहार, जयपुर और वडोदरा के राजपरिवारों के अलावा उनके ग्राहकों में बिहार और उत्तर-प्रदेश के जमींदार भी रहे हैं. पार्बती कहती हैं, "आखिरी हाथी हमने 14,000 रुपए में बेचा था."

वे खुद भी जंगल से छह हाथी पकड़ने का दावा करते हुए तफसील देती हैं, "हमें अपना शिकार तय करने में कई दिन लगते हैं. शिकार हमारे 'कुमकी' से कमजोर और ऊंचाई में छह फुट से बड़ा नहीं होना चाहिए. उसके बाद हम उसे झुंड से अलग करके तब तक पीछा करते हैं जब तक वह बेदम न हो जाए. उसकी सूंड पर एक रस्सा फेंका जाता है जिसके शरीर से छूते ही हाथी अपनी सूंड उठा देता है और हम फंदा कस देते हैं. फिर रस्से को अपने दो-चार 'कुमकी' की पीठ पर बांधकर पकड़े हाथी को घर ले आते हैं." उसे प्रशिक्षित करने में तीन साल लगते हैं. इस दौरान काफी धैर्य की जरूरत होती है.

आखिर धैर्य का फल मिलता है. पंखे जैसे कान और लंबी सूंड की मदद से अपने एक हाथी पर सवार होते हुए वे कहती हैं कि हाथियों से उन्हें स्नेह और साथ मिला है. वे उसे जंगल में ले जा रही हैं. उधर भटके हाथी अपने रास्ते लौट गए तो इधर पार्बती अपनी दिनचर्या पर लौट आई हैं. —कमलजीत रतन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रक्षेपास्त्र 'पृथ्वी'

सफलता के नए सोपान

पांच साल का महत्वाकांक्षी अनुसंधान आखिर रंग लाया

वे पांच क्षण ऐसे थे जब लगभग एक दर्जन वैज्ञानिकों की सांसें थम गई थीं. तरल ईंधन पर चलने वाला इंजन गरजा और लोगों की नजरें लांचिंग पैड पर गहरे लाल, सुनहरे और काले धुंए के विशालकाय बादल में से उठकर गति पकड़ते हुए रॉकेट पर टिक गईं. कुछ क्षणों में ही आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण क्षेत्र से दागा गया यह रॉकेट आसमान में लुप्त हो गया. उसके बाद जो कुछ हुआ वह सब एक नपा-तुला क्रम था. पहले तो मिसाइल वांछित ऊंचाई पर पहुंची, अपने निशाने की ओर बिजली की तरह लपकी और पलक झपकते ही उसे तहस-नहस कर डाला. उत्सुकता से भरी संसद में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने घोषणा की, "यह शानदार सफलता थी जिसमें परीक्षण के सभी लक्ष्य बखूबी पूरे हुए."

यह उत्सुकता बेमानी नहीं थी. पांच साल तक महत्वाकांक्षी अनुसंधान के एक लंबे, खर्चीले और कभी-कभी हतोत्साहित करने वाले दौर से गुजरने के बाद भारत के रक्षा वैज्ञानिकों ने जमीन-से-जमीन पर मार करने वाली पहली भारतीय मिसाइल 'पृथ्वी' का सफल परीक्षण पूरा किया. रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान (डीआरडीए) के एक चोटी के वैज्ञानिक की टिप्पणी थी, "हम शेखी नहीं बघार रहे हैं पर तय है कि यह मिसाइल अधिकांश लोगों की कल्पना से भी अधिक जोरदार है." इसी तरह हैदराबाद की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला (डीआरडीएल) के वैज्ञानिकों का दावा था कि उनकी यह मिसाइल अचूक होने और विनाश क्षमता के मामले में अपनी बराबरी वाली सोवियत मिसाइल स्कूद-बी, अमेरिका की लांस, चीन की टांग-फेंग, और इस्राएल की जेरिका-2 से भी कहीं बेहतर है. 150 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक अचूक निशाने के साथ 1000 किलो से ज्यादा विस्फोटक गिराने की क्षमता वाली यह मिसाइल भारत-पाकिस्तान मोर्चे की रंगत को बदल देने की ताकत रखती है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रक्षा विशेषज्ञ 'पृथ्वी' को मध्यम दूरी क्षमता वाले मिसाइल कार्यक्रम के संदर्भ में देखने लगे हैं जिनकी मदद से आवश्यकता पड़ने पर भारत काफी दूर तक परमाणु हमला भी कर सकता है.

ध्यान देने योग्य बात है कि परमाणु सामरिक भूमिका के अंतर्गत अपनी ऐसी ही लांस मिसाइल के साथ अमेरिका एक से दो किलो टन वाले विस्फोटक शीर्षों का उपयोग कर रहा है. इसीलिए 'पृथ्वी' के इस परीक्षण को पश्चिमी समाचार माध्यमों और हथियारों संबंधी पत्रिकाओं में गंभीरता से लिया जा रहा है. यदि 'पृथ्वी' का उपयोग परमाणु विस्फोटकों के लिए न भी किया जाए तो भी परंपरागत विस्फोटकों से ही यह भयंकर कहर ढाने की क्षमता रखती है. पश्चिमी विशेषज्ञ यह स्वीकार करते हैं कि इतना अचूक वार करने वाली मिसाइलों के होते परमाणु हमला अनावश्यक हो जाता है.

आवाज की गति से भी तेज उड़ान भरकर धरती-से-धरती पर तुरत-फुरत मार करने वाली इन मिसाइलों (एसएसएम) की मारक क्षमता का अंदाज खाड़ी युद्ध से भी मिल चुका है जिसमें ईरान और इराक सोवियत तथा चीनी एसएसएम मिसाइलों का इस्तेमाल एक दूसरे के शहरों पर करते आ रहे हैं. इन मिसाइलों के मुकाबले 'पृथ्वी' न

वैज्ञानिकों का कहना है कि पहली भारतीय मिसाइल 'पृथ्वी' अंतरराष्ट्रीय जगत में अपने मुकाबले के मिसाइलों से बेहतर है

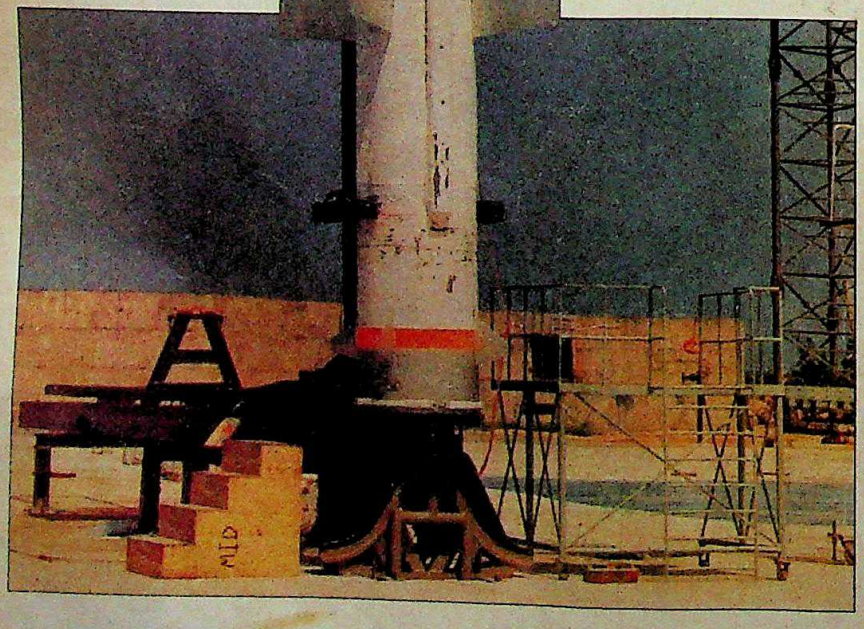

पृथ्वी का सफल परीक्षण: महत्वपूर्ण उपलब्धि

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

केवल दुगने विस्फोटक ले जा सकती है बल्कि दुगनी दूरी तक भी मार कर सकती है. एक विशेषज्ञ के शब्दों में, "एक ही हमले में पृथ्वी चार जगुआर विमानों जितना विस्फोटक पदार्थ अचूक निशाने पर ले जा सकती है और इसमें विमान या पायलट को जान बैठने का खतरा भी नहीं उठाना पड़ेगा."

इसके अलावा 'पृथ्वी' आर्थिक रूप से भी बहुत सस्ती पड़ेगी. 1990 में ऐसी एक मिसाइल की कीमत सवा करोड़ रुपए होगी जबकि एक जगुआर की कीमत 12 करोड़ रुपए से ज्यादा है.

वैज्ञानिकों का दावा है कि इसकी नियंत्रण प्रणाली को जाम करना सरल काम नहीं है. वैसे भी आवाज से अधिक गति होने के कारण जब तक दुश्मन के राडारों को इसकी भनक लगेगी तब तक इसके खिलाफ कोई कदम उठाने के लिए आवश्यक समय ही नहीं बचा रहेगा. इसके मुकाबले क्रूज मिसाइल इतनी धीमी है कि जवाबी मिसाइल या लड़ाकू विमान की मदद से उसे रास्ते में ही नष्ट किया जा सकता है. इसमें शक नहीं कि जून 1983 में 380 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुए इस महत्वाकांक्षी दस वर्षीय समेकित निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम (आइजीएम-डीपी) का यह एक महत्वपूर्ण अंग है.

इस अभियान के अंतर्गत हैदराबाद की प्रयोगशाला ने 'पृथ्वी' के अलावा दूसरी किस्म की मिसाइलों पर भी काम शुरू किया. छोटी दूरी से विमान नष्ट करने के लिए 'त्रिशूल', मध्यम दूरी तक जमीन से हवा में मार करने वाली 'आकाश' तथा थोड़ी दूरी से टैंकों को नष्ट करने वाली 'नाग' के विकास का कार्यक्रम प्रगति पर है. इनमें से 'त्रिशूल' के परीक्षण पूरे हो चुके हैं. यह मिसाइल फ्रांस के क्रोटेल और पाकिस्तान के कटा स्थित परमाणु संयंत्र की रक्षा की नैनात ब्रिटिश 'रैपियर' मिसाइलों की जगह लेगी है. 'नाग' के बारे में कहा जाता है कि यह फ्रांसीसी टैंकभेदी 'मिलान' और अमेरिकी 'टो' से बेहतर है. मगर मिसाइलों की इस शृंखला में सबसे महत्वपूर्ण 'आकाश' को माना जा रहा है.

सच तो यह है कि इन सभी प्रणालियों को अंतिम रूप मिलने के रास्ते में से अभी भी कई बाधाएं और हटाई जानी बाकी हैं. रक्षा-मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार वी.एस. अरुणाचलम कहते हैं, "इन परियोजनाओं में धीरज की जरूरत है." लेकिन यह तय है कि 'पृथ्वी' की सफलता ने रक्षा वैज्ञानिकों का आत्मविश्वास इतना बुलंद कर दिया है कि अनुसंधान के बाकी रास्ते को पूरा करने में ज्यादा कठिनाई नहीं होनी चाहिए. —शेखर गुप्ता

रक्षा खर्च

कटौती की मार

रक्षा मंत्रालय में खर्च कम करने का दौर आ गया है. पांच वर्षों तक हथियारों की खरीद में जमकर पैसा खर्च करने के बाद इस शताब्दी के सबसे भयंकर सूखे के कारण सेना के आधुनिकीकरण की कोशिशों पर विराम लगने का संकट खड़ा हो गया है.

वैसे 1988-89 के रक्षा बजट में 1000 करोड़ रुपए का इजाफा करके उसे 13,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है पर 9.8 फीसदी की दर वाली मुद्रास्फीति को देखते हुए वास्तविक अर्थ में रक्षा मद में बढ़ोतरी कम ही हुई है. ऊपर से श्रीलंका और सियाचिन अभियान के खर्च का बोझ है ही. अभी तक प्रतिरक्षा को हर साल मुद्रास्फीति की दर से 4-5 फीसदी ज्यादा की वृद्धि दी जाती थी. पिछले साल तो यह बढ़ोतरी 23 फीसदी थी.

चार्ट: बी.के. शर्मा

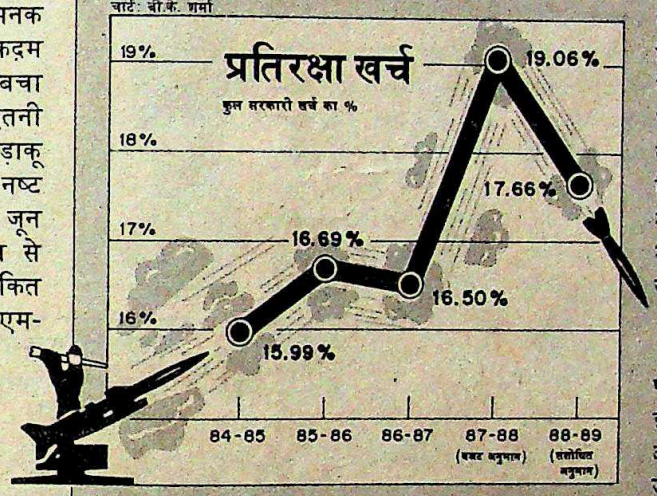

अब जबकि योजना बनाने वाले बचत पर ध्यान देने लगे हैं तो तीनों सेनाओं के आधुनिकीकरण की कोशिशों को धक्का लगना स्वाभाविक ही है. विशेषज्ञों का मानना है कि कटौती से निम्नलिखित रक्षा उपकरणों की खरीद रुक जाएगी:

► भारतीय वायु सेना के लिए 1000 करोड़ रुपए की लागत वाले अत्याधुनिक जेट ट्रेनर की खरीद खासकर ऐसे समय रुक सकती है जबकि वायु सेना को लग रहा है कि विमान दुर्घटनाएं बढ़ने का एक संभावित कारण उसके पास कोई अच्छा कारण कोई अच्छा ट्रेनर जहाज का न होना भी है. फिलहाल सबसे आधुनिक ट्रेनर 30 साल पुराना हॉकर हंटर है जो जल्दी विदा लेने वाला है.

► टैंक विध्वंसक हल्के हेलीकॉप्टरों की खरीद का भी प्रस्ताव है, जिस पर 500 करोड़ रुपए खर्च होने की उम्मीद है. इटली की 'ऑगस्टा' और प. जर्मनी की 'मेसर-श्मिड्ट' यह ऑर्डर पाने की होड़ में हैं. मध्यम क्षमता वाले हेलीकॉप्टरों की, जिसमें अधिक संभावना डॉल्फिन की है, खरीद के प्रस्ताव का भी शायद यही अंजाम होगा.

► थल सेना के लिए स्विस आरलिकान विमानभेदी गनों और अत्याधुनिक संचार उपकरणों की खरीद का मामला भी लटक सकता है. दो अतिरिक्त डिवीजन (40,000 सैनिकों के) बनाने के प्रस्ताव पर भी बजट कटौती का असर पड़ेगा. ये डिवीजन आंतरिक सुरक्षा और श्रीलंका जैसे अभियानों के लिए गठित किए जाने हैं. वायु सेना को भी अपने खर्चों में कटौती करने की तैयारी करनी पड़ रही है. यह कटौती ईंधन के खर्च में होगी. अर्थात पायलटों को प्रशिक्षण उड़ानें कम करनी पड़ेंगी.

नौसेना पर इन कटौतियों की कम मार पड़ी है तो इसलिए कि उसकी खरीद के मामले काफी परिपक्व हो चुके हैं. पर पश्चिम जर्मनी से दो और एचडीडब्ल्यू पनडुब्बियों की खरीद का करार रद्द होने से पैसे जरूर बचेंगे.

कटौतियों का कारण वित्तीय तंगी ही है. इसलिए खरीद वाले अधिकांश प्रस्ताव फिलहाल टल भर जाएंगे. इनकी जगह देश में ही हथियार विकसित करने का नीतिगत फैसला भी नहीं हुआ है क्योंकि खुद रक्षा कारखानों का बजट आधा कर दिया गया है.

अब आधुनिकीकरण के लिए एक ही रास्ता बचता है कि देशी प्रतिरक्षा उद्योग अपना सामान निर्यात करके विदेशी मुद्रा कमाए. इस मामले में जल्दी ही नीतिगत फैसला होने की उम्मीद है. अगर ऐसा होता है तो इसका अर्थ हुआ कि जो बात पिछले तीन दशकों में विशेषज्ञों के बार-बार कहने से भी नहीं हो रही थी वह एक साल सूखा पड़ने से ही हो जाएगी.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मादक दवाएं

सुनियोजित तस्करी का मजबूत शिकंजा

बेहिसाब मुनाफे का खतरनाक खेल

पिछले 5 साल भारत की तस्करी दुनिया में जबरदस्त बदलाव के साल रहे हैं. चांदी ने तस्करों का मोह भंग किया तो हेरोइन, चरस, गांजे आदि से हाथोहाथ करोड़ों बना लेने की संभावनाओं ने आशा का नया नशा पैदा कर दिया. नतीजतन अब भारत नशीली दवाओं की तस्करी का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है. इस काले धंधे के विभिन्न पहलुओं की संवाददाता ***विजय क्रान्ति*** *द्वारा पड़ताल :*

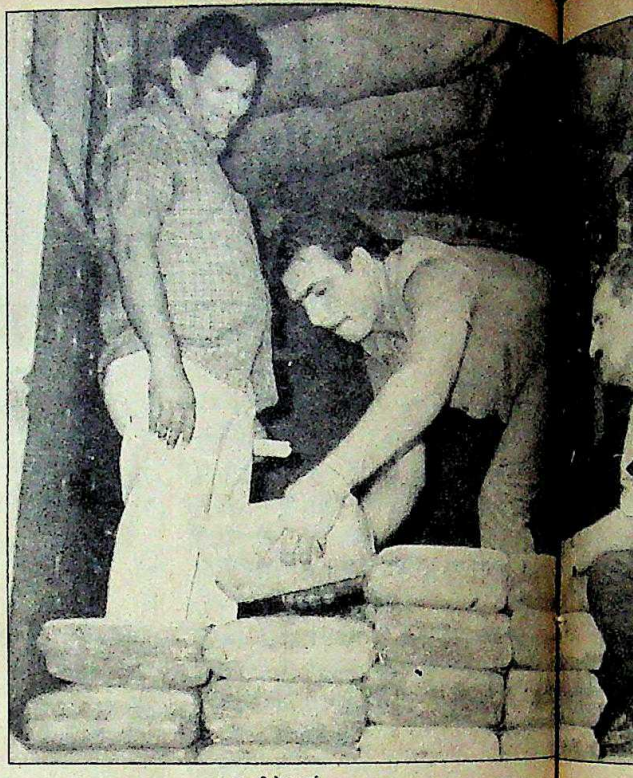

ते ईस फरवरी के दिन दिल्ली के गगन विहार में एक घर के सामने एक मारुति कार में से बोरियों में बंधे बंडल ट्रक में लादे जा रहे थे. आसपास सादे कपड़ों में फैले हुए दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के जासूस ट्रक और कार के बीच हो रही इन हरकतों पर बारीकी से आंखें गड़ाए हुए थे. अचानक ही वे हरकत में आए और पलक झपकते ही वहां काम में लगे लोगों को धर दबोचा.

कार की तलाशी लेने पर उसमें से 105 किलोग्राम चरस मिली. पता चला कि ट्रक में बनी गुप्त खोहों में भी 315 किलो चरस और भी थी. अब बारी आई घर की जिसमें एक अफगानिस्तानी शरणार्थी परिवार रह रहा था. वहां से 237 किलो चरस का एक और जखीरा बरामद हुआ—कुल मिलाकर 657 किलो चरस. अगर यह माल तस्करों की योजना के अनुसार विदेशी बाजारों में पहुंच गया होता तो इस एक सौदे की बदौलत ही धंधे में लगे लोगों की जेब में लगभग 16.5 करोड़ रुपए पहुंच जाते—रिलायंस इंडस्ट्रीज की पिछले वर्ष के कुल मुनाफे (टैक्स कटने से पहले 14.5 करोड़ रुपए) से भी दो करोड़ ज्यादा.

मगर यह तो रही बात एक 'छोटे से' मामले की. नया साल शुरू होने के दिन से ही अखबारों में जिस तरह एक के बाद एक करोड़ों रुपए की हेरोइन, अफीम और गांजा पकड़े जाने की खबरें छप रही हैं वे सब उस खतरे की ओर इशारा करने के लिए काफी हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था और राजनैतिक स्थिरता के सिर पर मंडरा रहा है. इस साल के पहले दो महीनों के भीतर ही देश भर में 710 किलो हेरोइन, 10,519 किलो चरस, 110 किलो अफीम और 5922 किलो गांजा पकड़ा गया जिसकी विदेशों में कीमत 1003 करोड़ रुपए बनती है. यह 1986 के दौरान बिरला, टाटा और रिलायंस समेत चोटी के 15 औद्योगिक घरानों के कुल मुनाफे से ज्यादा है.

पिछले साल पकड़े गए माल की अंतरराष्ट्रीय कीमत 3490 करोड़ रु. थी, जबकि 1981 में यह राशि मात्र 8 करोड़ थी. लेकिन अपने ठिकानों तक जा पहुंचने वाली.

नक्शा: बी.के. शर्मा

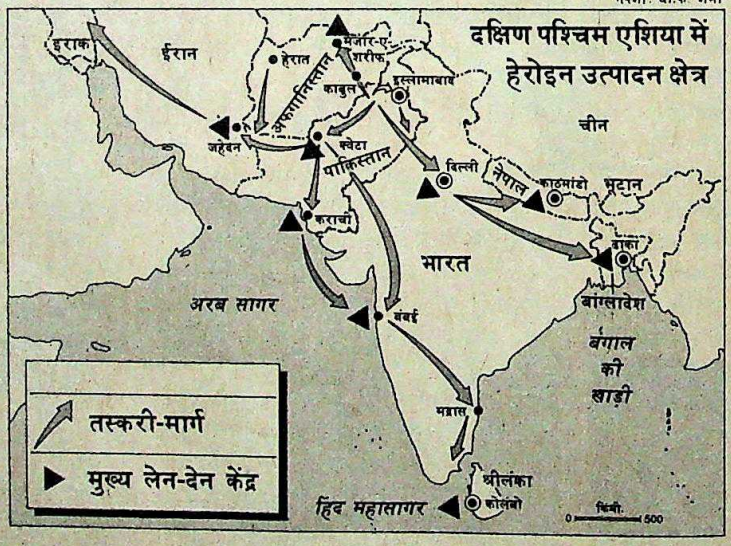

दवाओं की मात्रा कितनी रहती है इस बारे में केवल अनुमान ही लगाए जा सकते हैं. कुछ अनुमानों के अनुसार यह मात्रा तीन गुना होती है जबकि कुछ लोग इसे दस गुना तक मानते हैं.

देश भर में नशीले पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध गतिविधियों में तालमेल बिठाने वाले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक बी.वी. कुमार के शब्दों में, "नशीले पदार्थों का सामाजिक खतरा तो है ही, उससे भी कहीं बड़ा खतरा यह है कि यह सारा पैसा जिन लोगों के हाथों में केंद्रित हो रहा है वे न तो इस समाज के दोस्त हैं और न इस देश के."

वैसे इंटरपोल की ताजा रिपोर्ट ब्यूरो के लिए सांत्वना देने वाली है. इसमें कहा गया है कि भारत से यूरोप जाने वाली हेरोइन की मात्रा में कमी आने लगी है. 1985 में यूरोप के देशों में पकड़ी गई हेरोइन में तुर्की के 61 फीसदी के मुकाबले भारत का हिस्सा 36 फीसदी था. पिछले साल यह अनुपात उलट गया और तुर्की के 61 फीसदी हिस्से के मुकाबले केवल 7 फीसदी ही रहा.

भारत के लिए परेशान करने वाली बात

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

घी के डिब्बों में हेरोइन और चरस का जखीरा; और (बाएं) तस्करी का माल

मात्रा कितनी
बारे में केवल
लगाए जा सकते
मानों के अनुसार
न गुना होती है
लोग इसे रख
नते हैं.
र में नशीले
स्करी के विरुद्ध
में तालमेल
ने नारकोटिक्स
के महानिदेशक
र के शब्दों में,
र्थों का सामान
तो है ही, उनसे
ा खतरा यह है
रा पैसा जिस
रहा है वे न तो
न इस देश के
रिपोर्ट ब्यूरो के
समें कहा गया है
ली हेरोइन की
1985 में यूरोप
में तुर्की के 10
का हिस्सा 35
अनुपात उलट
सदी हिस्से के
रहा.
रने वाली बात

यह है कि यहां से पश्चिमी और दूसरे देशों की ओर जाने वाली ये नशीली दवाएं ज्यादातर पाकिस्तान से आती हैं. 1986 में भारत में पकड़ी गई 2621 किलो हेरोइन में से 1983 किलो यानी लगभग 75 फीसदी माल पर पाकिस्तानी मार्के पाए गए. 1987 में ऐसी हेरोइन की मात्रा 83.5 फीसदी (2716 में से 2269 किलो) थी. इसी तरह 1987 में पकड़ी गई कुल हेरोइन में से 64 फीसदी माल भारत-पाक सीमा से लगने वाले इलाकों में पकड़ा गया.

आठवां दशक शुरू होने तक दुनिया भर को सप्लाई होने वाली अफीम और उससे तैयार होने वाली हेरोइन, मारफीन तथा ब्राउन शुगर जैसी दवाएं बर्मा-लाओस-थाईलैंड के 'सुनहरे त्रिकोण' में तैयार की जाती थीं. बाद में धीरे-धीरे इस धंधे ने पाकिस्तान-अफगानिस्तान-ईरान के 'सुनहरे चंद्र' (गोल्डन क्रिसेंट) में जड़ें जमा लीं.

इस दौरान पश्चिमी देशों में जिस तरह पाकिस्तानी यात्रियों तथा पाकिस्तानी जहाजों से नशीली दवाएं बरामद होने लगीं उससे पाकिस्तानी तस्कर सिंडिकेटों के लिए नई समस्या पैदा कर दी. उधर अमेरिका में बढ़ते हुए हेरोइन उपयोग के कारण भी कोकीकी दवाब बढ़ने लगा था. वैसे भी उस ओर में दवाओं की तस्करी के लिए भारत में केवल 3 साल की कैद का प्रावधान था.

नवंबर 1985 में मादक दवा और नशीले पदार्थों संबंधी कानून लागू होने के बावजूद सजा की अधिकतम सीमा पहली बार 10 साल और दूसरी बार 15 साल तक ही सीमित है. जबकि ईरान, थाइलैंड और हांगकांग में नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए मौत की सजा दी जाती है.

भारत-पाकिस्तान की लंबी बियाबान सीमा इस काम के लिए काफी अनुकूल सिद्ध हुई और देखते ही देखते दिल्ली और बंबई इन दवाओं की तस्करी के नए अंतरराष्ट्रीय अड्डे बन गए. यह परिवर्तन भारत में काम करने वाले तस्करों, पंजाब के कुछ आतंकवादी गुटों, अफगान शरणार्थियों के एक वर्ग और कुछ विदेशियों के लिए बिल्ली के भाग्य से छींका टूटने जैसा सिद्ध हुआ. पिछले साल अगस्त में कुख्यात आतंकवादी हरजिंदर सिंह 'जिंदा' की गिरफ्तारी से खुफिया एजेंसियों को हेरोइन की तस्करी में पंजाब के कुछ आतंकवादी गुटों की सक्रियता के सुराग मिले. इस साल जनवरी में लुधियाना में दो ट्रकों से 180 करोड़ रुपए की हेरोइन पकड़े जाने पर की गई जांच से संकेत मिले कि तस्कर सिंडिकेटों के कुछ सरगना अमृतसर के धार्मिक स्थलों से अपनी गतिविधियों का संचालन करते हैं. तस्करी से प्रभावित इलाकों में सबसे प्रमुख स्थान अमृतसर और फिरोजपुर जिलों का है जो आतंकवाद के भी गढ़ हैं.

दूसरी दवाओं के मुकाबले हेरोइन की तस्करी के बारे में दिल्ली पुलिस के उपायुक्त आमोद कंठ बताते हैं, "हेरोइन को तस्करों द्वारा बढ़ावा दिए जाने का एक कारण तो यह है कि बहुत जल्दी ही इसकी लत पड़ जाती है. दूसरे, छोटी मात्रा के कारण इसे आसानी से कहीं छिपाया जा सकता है. और तीसरी बात है मुनाफा— न्यूयॉर्क की गलियों में पहुंचते-पहुंचते इसकी कीमत एक करोड़ रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच जाती है."

पेशावर और कराची की हेरोइन फैक्ट्रियों से निकलने वाली अच्छी किस्म की हेरोइन (90 फीसदी) की कीमत 30 हजार रुपए प्रति किलो होती है जो दिल्ली या बंबई पहुंचने तक एक लाख रुपए हो जाती है. बाद में एम्स्टरडम, पेरिस या न्यूयॉर्क में पहुंचने पर दाम एक लाख डॉलर तक जा पहुंचता है और गलियों में नशेड़ियों के हाथों में आने पर यह कीमत 10 लाख डॉलर यानी एक करोड़ रुपए प्रति किलो से भी ऊपर पहुंच चुकी होती है यानी 333 गुना मुनाफा.

हेरोइन के प्रति बढ़ते इस आकर्षण का एक उदाहरण ब्यूरो द्वारा 12 फरवरी को पकड़े गए एक मामले से मिलता है. कई महीनों तक एक के बाद एक सूत्र पकड़ते हुए ब्यूरो के जासूसों ने नई दिल्ली के नेहरू प्लेस में मसालों और चावल का निर्यात करने वाले एक व्यापारी बी.डी. टंडन को जा दबोचा और उसके केबिन से 3 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की 3.180 किलोग्राम हेरोइन बरामद की. ब्यूरो सूत्रों के अनुसार उसने माना कि पिछले दो साल में उसे व्यापार में 10 लाख रुपए का घाटा हो चुका था. लिहाजा घाटा पूरा करने के लिए वह हेरोइन के धंधे में आ गया. जानकार ब्यूरो सूत्रों के अनुसार घंटा भर पहले आए इस पैकेट को

पश्चिम यूरोप में बरामद हेरोइन: कहां से कितनी आई?

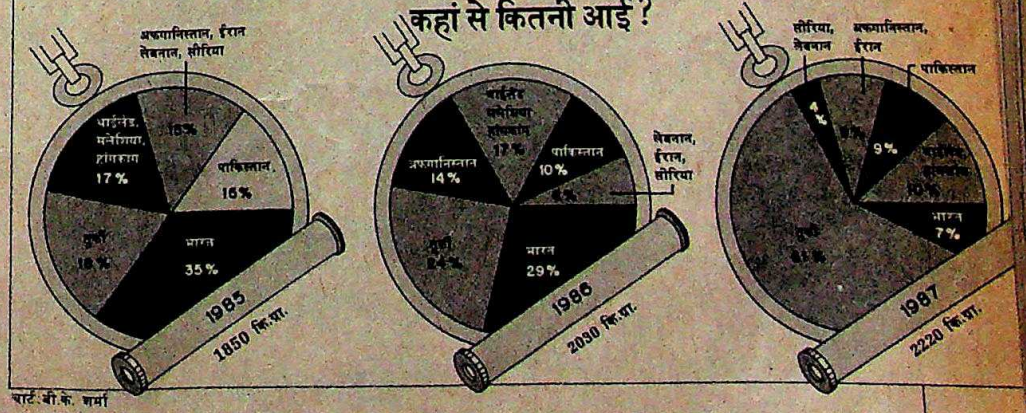

चार्ट: बी.के. शर्मा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

10 साल खर्च कर के सिर्फ एक पशु-टीके का विकास सार्थक रहा !

यह बछड़ा खुरपका और मुखपका की भयानक बीमारी से बच गया.

हॅक्स्ट को इसी तरह लाखों जानवरों की लगातार चिंता रहती है. और इलाज की खोज चलती ही रहती है. कभी-कभी तो एक दवा की खोजबीन में 8,000 सम्मिश्रणों का परीक्षण होता है. इसमें दस-दस साल तक लग जाते हैं. साथ ही असीम साधनों की लागत.

लेकिन इस से भारत में कहीं-न-कहीं जीवन-दात्री गाय का भविष्य सुरक्षित हो जाता है. जीवन-लेवा परिस्थिति से बचाव भी. पूरा-का-पूरा झुंड बच जाता है. तब, इन में से हरएक जीवन, जो बच जाता है या सुधरता है, पूरे प्रयत्न को सार्थक बना देता है.

आज हॅक्स्ट का खुरपका-मुखपका का टीका पशुओं, भेड़ों और बकरियों की इस खतरनाक बीमारी से बचाव करता है.

हॅक्स्ट की दूसरी, जानवरों के लिए जीवन-रक्षक दवाएं, तबाही मचाने वाली आम महामारियों को रोकने में मदद करती हैं. हॅक्स्ट के पशु-स्वास्थ्य उत्पादन, जैसे कीटकहारी, पीड़ाहारी और ज्वरहरी टीके, पशु-बीमारियों से छुटकारा दिलाने में मदद देते हैं. और पोषक आहार-पुरक, मुर्गी-पालन और सुअर-पालन के संतुलित आहार के लिए, विशेषकर बनाए गए हैं. ताकि भारतीय पशुधन सुरक्षित रहे और स्वस्थ उत्पत्ति करे.

हॅक्स्ट पौधों, जानवरों और मनुष्यों का जीवन-स्तर ऊपर उठाने के लिए वचनबद्ध है. लगातार खोजबीन और पशु-चिकित्सा के उत्पादनों, औषध-रसायनों और खेती-रसायनों के विकास से जीवन को सुरक्षित और विकसित करने के लिए. पशुओं की देखभाल के कार्यक्रमों, जैसे कीटहरी मोहिमों के द्वारा. और भारत में, हर संभव दृष्टि से जीवन-स्तर ऊपर उठाकर.

हॅक्स्ट इण्डिया

पशु-स्वास्थ्य उत्पादनों के निर्माता

क्योंकि जीवन मूल्यवान है

Hoechst

ULKA-HI-2.80

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कुछ मिनट बाद अगले आदमी तक पहुंचाने के लिए उसे 2 लाख रुपए दे ज्यादा मिलने वाले थे. जांच के दौरान ही टंडन अचानक जासूसों को चकमा देकर बाहर भागा और बालकनी से 35 फीट नीचे कूदकर आत्महत्या कर ली.

हेरोइन तथा दूसरी मादक दवाओं का यह धंधा क्या कभी खत्म हो पाएगा? इस सवाल के जवाब में कुमार कहते हैं, "जिस धंधे में बिना कोई बड़ा काम किए हाथोहाथ लाखों रुपए बन जाते हों भला उसे लोग आसानी से कैसे छोड़ देंगे. वैसे हमारा लक्ष्य तो यही है कि तस्करों को इतना परेशान कर दिया जाए कि उन्हें अपना धंधा भारत से लपेटकर भागने पर मजबूर होना पड़े." अपने इस काम में ब्यूरो को कुछ प्रभावी सफलताएं भी मिली हैं. गत नवंबर में ब्यूरो की जानकारी के आधार पर न्यूयॉर्क में 9.5 किलो हेरोइन के साथ एक इतालवी फाल्को फ्रांसिस्को, एच.एस. गाबा, जीनत अहमद और मंजुला बेन देसाई को हिरासत में लिया गया. होटल के कमरे से पकड़ी गई हेरोइन मशहूर 'क्राफ्ट' पनीर और 'वाउंटी' चाकलेट के रैपरों में बहुत सफाई के साथ पैक की हुई थी.

न्यूयॉर्क से इस सफलता की खबर के साथ ही ब्यूरो ने दिल्ली में छापे मारकर अशोक होटल से जसबीर सिंह संधू उर्फ 'जस्सी' और स्टेट बैंक डकैती के सजायाफ्ता अभियुक्त विपिन जग्गी समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया. पकड़े लोगों में सुखदेव सिंह चहल उर्फ 'मंकी' भी था जो मादक दवाओं के एक मामले में ब्रिटेन में 12 साल की सजा सुनाए जाने से पहले ही फरार होकर भारत आ गया था.

ब्यूरो ने पिछले साल सितंबर में एक और सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया जिसका संचालन दिल्ली के वसंत विहार में जोगिंदर मोहन मल्होत्रा उर्फ जिंदू मल्होत्रा के हाथ में था. उसे अपनी एक साथी मंजू नरूला के मालवीय नगर निकास पर लगभग 10 किलो बढ़िया हेरोइन के साथ पकड़ा गया. यह माल कुछ प्रसिद्ध कंपनियों के घी और अचार के डिब्बों के पेंदे काटकर उनमें असली माल के स्थान पर इस तरह भरा हुआ था कि डिब्बे एकदम असली लगें. ब्यूरो सूत्रों के अनुसार इससे पहले एक एंबेसेडर कार के दरवाजों के भीतरी पैनल में रखकर हेरोइन दिल्ली लाई गई थी. मल्होत्रा के अलावा इस मामले में उसके भाई सुरिंदर मल्होत्रा और दो साथियों युधिष्ठिर कुमार तथा एन.पी. सिंह को भी गिरफ्तार किया गया.

6 जनवरी को बंबई के राजस्व विभाग के जासूसों ने बंदरगाह से निर्यात के लिए तैयार तौलियों, चादरों और दूसरे सूती कपड़ों वाली 280 गांठों का एक कंटेनर पकड़ा जिनमें से 77 गांठों में 4050 किलो हशीश भरी हुई थी. पिछले साल के अंत में ब्यूरो ने दिल्ली के निकट नोएडा और हरियाणा के लाडवा कस्बे में मेथाक्विलोन (मैंड्रेक्स) की दो फैक्ट्रियां पकड़ीं. लाडवा की फैक्ट्री से शामलाल को पकड़ा गया जिस पर आरोप है कि वह 'लिली फार्मास्युटिकल्स' की आड़ में यह धंधा चला रहा था.

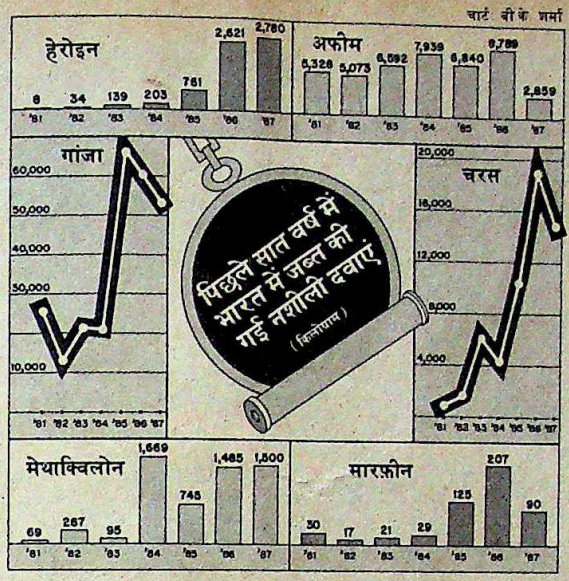

भांग की पैदावर के अनुकूल जलवायु होने के कारण देश भर में चोरी-छिपे चरस और गांजा का धंधा भी एक लंबे समय से चलता आ रहा है. कई इलाकों में तो जंगली और पहाड़ी जगहों पर बाकायदा नर्सरियां विकसित करके भांग की खेती की जाती है.

पिछले कुछ महीनों से आ रहे संकेतों से लग रहा है कि हेरोइन तस्करी का धंधा अब भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में भी पांव पसारने लगा है. मणिपुर के निकट बर्मा से लगने वाली सीमा पर हेरोइन उत्पादन के समाचार परेशान करने वाले हैं.

पिछले दो साल से पश्चिमी देशों की सरकारें भारत के साथ मिलकर हेरोइन तस्करी रोकने के प्रति भारी उत्सुकता दिखाती आ रही हैं. आजकल यहां अमेरिका, पश्चिम जर्मनी, कनाडा और ब्रिटेन की मादक दवा एजेंसियों के प्रतिनिधि तस्करी विरोधी गतिविधियों में भारत सरकार को सहयोग देने के लिए तैनात हैं.

इन देशों के इस अति उत्साह के बारे में कुमार चुटकी लेते हुए कहते हैं, "क्योंकि उनके देशों में दवाओं के कारण समस्या पैदा हो रही है इसलिए वे हर तरह की सहायता देने को तैयार हैं. लेकिन जब हमें अपने यहां के आर्थिक अपराधियों के बारे में जानकारी की जरूरत होती है. तब यही सरकारें अपने यहां के गोपनीयता कानूनों की दुहाई देकर हाथ पीछे खींच लेती हैं." मगर इसके बावजूद कुमार इस बात से संतुष्ट हैं कि इस अंतरराष्ट्रीय सहयोग से मादक दवाओं की तस्करी के मोर्चे पर आशा की किरणें दिखाई देने लगी हैं.

लेकिन इंटरपोल का कहना है कि मई-जून में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पकने वाली अफीम से 15 से 18 टन हेरोइन तैयार की जाने वाली है. तय है कि 15,000 करोड़ रुपए कीमत वाले इस जहर को तस्करों की बिरादरी दुनिया भर के 5 करोड़ नशेड़ियों तक पहुंचाने की कोशिश करेगी. देखना यह है कि तस्करों और खुफिया एजेंसियों के बीच चलने वाली इस आंख मिचौनी में कौन किसे छकाता है?

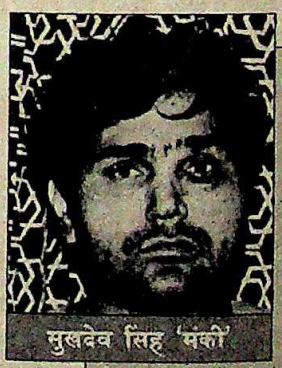
सुखदेव सिंह 'मंकी'

विपिन जग्गी

नशीली दवाओं में मुनाफे के भारी अनुपात के कारण तस्करी का पैसा उन हाथों में केंद्रित हो रहा है जो न तो समाज के दोस्त हैं और न इस देश का भला सोचने वाले

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विमान चयन

मकसद का मजाक

जटिल चयन प्रक्रिया के बावजूद उपयुक्त विमानों का चुनाव नहीं

भारत में विमानों के चयन की प्रक्रिया बेहद धीमी और जटिल है. किसी भी प्रस्ताव को लगभग आधा दर्जन समितियों के जाल में से गुजरना पड़ता है. यह सारी कवायद और जहमत और इन सब में हुई देरी सार्थक मानी जाती अगर चुना गया विमान आवश्यकताओं पर खरा उतरता. लेकिन दुर्भाग्य से एअर इंडिया और इंडियन एअरलाइंस के पिछले कुछ वर्षों के अनुभव तो यही बताते हैं कि विमान जिस खास मकसद के लिए चुने गए उस पर अक्सर खरे नहीं उतरे.

ऐसा अभी दो मामलों में हुआ—1986-87 में बोइंग-707 को बदलने के विशेष उद्देश्य से एअर इंडिया द्वारा खरीदी गई एअरबस ए-310 और इंडियन एअरलाइंस द्वारा घरेलू उड़ानों के लिए पुराने बोइंग-737 को बदलने के लिए ए-320 की खरीद के मामले में. एअर इंडिया का ए-310 उन मार्गों पर उड़ान नहीं भर रहा जिनके लिए इसका चयन किया गया था. इस विमान कंपनी को अपनी दिल्ली-सोवियत संघ सेवा जारी रखने के लिए सोवियत संघ से विमान पट्टे पर लेने जैसा बेमिसाल कदम उठाना पड़ा. घरेलू उड़ान वाले ए-320 विमानों का सौदा दो कारणों से खटाई में पड़ गया है. इंडियन एअरलाइंस ने वी-2500 इंजन चुना था जो कि दस्तावेजों में अपने प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले कम ईंधन खपत करने वाला दिखाया गया था. लेकिन इस इंजन ने इसके निर्माताओं को ही परेशानी में डाल

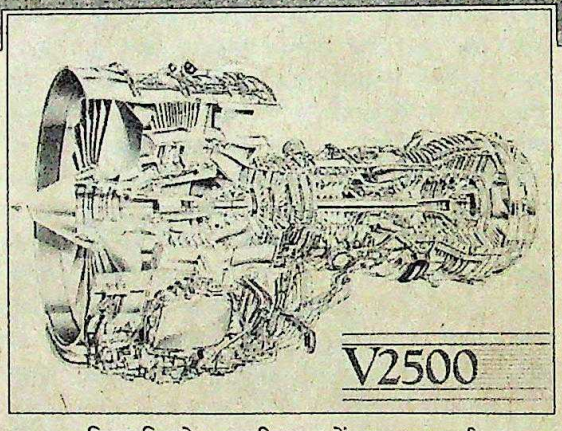

ए-320 विमान और इसका समस्याग्रस्त इंजन

दिया जिससे प्रमाणीकरण में रुकावट आई.

इस बीच एअरबस इंडस्ट्री ने कामचलाऊ व्यवस्था के तहत इंडियन एअरलाइंस को उसकी जरूरतों के मुताबिक पट्टे पर विमान तब तक (1989 तक) उपलब्ध कराने की पेशकश की जब तक नए विमान नहीं दिए जाते. लेकिन यह व्यवस्था भी खटाई में पड़ गई है. और अब हालत यह है कि घरेलू उड़ानों में यात्रियों की वृद्धि दर जो 1980 और 1984 के बीच 12 प्रतिशत थी, 1985-88 के बीच घटकर 7 प्रतिशत रह गई. इस तरह इंडियन एअरलाइंस पिछले तीन वर्षों में 90 करोड़ रुपए की कमाई से वंचित रह गई है.

एअर इंडिया वाली चयन समिति के अध्यक्ष खुद इसके संस्थापक जे.आर.डी. टाटा थे. उन्होंने ए-310 के बदले बोइंग-767 का चुनाव किया था. एअर चीफ मार्शल दिलबाग सिंह की अध्यक्षता वाली इंडियन एअरलाइंस की चयन समिति में इसके प्रबंध निदेशक और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव तक शामिल थे. इस समिति ने बोइंग-757 को चुना. लेकिन जैसी कि उम्मीद थी, एअरबस इंडस्ट्री के ए-320 विमान का चयन कर लिया गया. ऐसा ही उलटफेर एअर इंडिया के मामले में किया गया. टाटा समिति ने बोइंग-767 की सिफारिश की लेकिन बाद में एअरबस को मंजूरी मिल गई.

टाटा समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि '707' विमानों का स्थान लेने वाले विमानों की क्षमता इतनी होनी ही चाहिए कि वे भारत से रोम, सिंगापुर, जापान और मॉरिशस की बिना रुके उड़ान भर सकें. जब ए-310 एअर इंडिया की जरूरतें पूरी नहीं कर पाया तो ऐसे छह विमानों की खरीद के बाद भी एअर इंडिया ने अधिकतर मार्गों पर विशाल बोइंग-747 चलाना ही बेहतर समझा. जापान, आस्ट्रेलिया और रोम के लिए भी '747' विमान ही उड़ान भरते हैं जबकि आम तौर पर इन मार्गों पर यात्रियों की कम संख्या इतने बड़े विमानों को लगाने के लिए तर्कसंगत नहीं लगती.

दिल्ली-मॉस्को मार्ग पर एअर इंडिया ने पहले तो ए-310 की उड़ानें शुरू कीं लेकिन सर्दियों में दो इंजन वाले इन विमानों में परेशानी आने लगी तो इन्हें हटा लिया गया. एअर इंडिया ने अब एक आइएल-62 विमान उधार लिया है. यानी उसने या तो 707 के स्थान पर लिए जाने वाले विमान और यात्रियों की संख्या का अनुमान

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chenn

अशोक कुमार और उनकी पोती अनुराधा

३ कमाल वाला टूथपेस्ट क्यों हमने भी अपनाया"

"मानिए या ना मानिए, पर मैंने तो सचमुच अपना टूथपेस्ट बदल डाला है! अब मैंने अपनाया है **लौंग, फ्लोराइड** और **मिन्ट** के ३ कमाल वाला प्रूडेन्ट. है मेल खाना अच्छा, मानों दांतों का साथी सबसे सच्चा!
अनुराधा ने एक और खूबी पायी – प्रूडेन्ट की सॉफ्ट-स्क्वीज़ ट्यूब! सदा रहे साफ़-सुथरी. ऐसी खूबी और किसी टूथपेस्ट में कहां है!"

मुफ्त! दांतों की देखभाल के लिए रंगीन पुस्तिका. सीमित संख्या में.
लिखिए: पारले प्रॉडक्ट्स प्रा. लि., निर्लोन हाउस, २५४-बी, डॉ. ए.बी. रोड, बम्बई ४०० ०२५.

प्रूडेन्ट में हैं कमाल ३, दांतों के लिए बेहतरीन

पारले

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

THE EDGE-B/87/PP/107-hn

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लगाने में गलती की, अथवा ए-310 के प्रस्ताव को जानबूझकर स्वीकार किया जबकि यह विमान कसौटी पर खरा नहीं उतरता. यदि 707 वाले मार्ग पर यात्रियों की बढ़ोतरी के कारण 747 विमानों को लगाना तर्कसंगत था तो और अधिक 747 विमानों की खरीद का ही आदेश दिया जाना चाहिए था. लेकिन अपने अधिकांश मार्गों पर यात्रियों की कम संख्या के बावजूद एअर इंडिया 747 विमानों का ही प्रयोग कर रही है तो फिर इसने ए-310 विमान खरीदे ही क्यों थे? एअर इंडिया के अधिकारी इस प्रश्न का विश्वसनीय जवाब देने में बेहद मुश्किल महसूस करते हैं.

एअरलाइंस के अधिकारी बताते हैं कि जब इस इंजन का चुनाव किया गया था इसके प्रतिद्वंद्वी सीएफएम-56 के मुकाबले इसमें 3 से 4 प्रतिशत ईंधन की खपत कम होने का दावा किया गया था. ये दावे अब कुछ तो कमजोर हो ही गए हैं.

ऊपरी तौर पर तो लगता है कि इंडियन एअरलाइंस वी-2500 इंजन को लेकर परेशान नहीं है. प्रबंध निदेशक गैरी पायस ने बताया, "अभी हमने वी-2500 की जगह सीएफएम-56 इंजन लेने का मन नहीं बनाया है. एअरबस ने हमें आश्वस्त किया है कि ए-320 विमानों की सप्लाई में देरी नहीं होगी. और एअरबस उस अनुबंध से बंधी है जिसके अनुसार इंजन द्वारा अतिरिक्त ईंधन खपत होने पर वह इसका मुआवजा देगी." उधर 'इंटरनेशनल एअरो इंजन्स' के प्रबंधक एलन ब्रद्रर्स ने कहा, "वी-2500 की तकनीकी दिक्कत दूर हो गई है. और इस साल जून तक इसे उड़ान संबंधी प्रमाणपत्र मिल जाने की पूरी उम्मीद है."

लेकिन इंडियन एअरलाइंस को एअरबस इंडस्ट्री से पिछले तीन वर्षों में विमान न मिल पाने और उसके कारण हुए वित्तीय घाटे की क्षति पूर्ति का कोई प्रावधान नहीं है. 1985 में घरेलू उड़ानों में यात्रियों की संख्या में 11 से 12 प्रतिशत की वृद्धि दर से तालमेल बिठाने के लिए तुरंत और विमानों की जरूरत महसूस हुई. बोइंग-757 विमान उस साल सितंबर में ही मिलने वाले थे जबकि पहला ए-320 विमान 1989 के मध्य में ही मिल पाता. इस बड़े अंतराल में एअरबस इंडस्ट्री ने कम-से-कम चार ए-300 विमान देने का वायदा किया. और सात बोइंग-737 आसान पट्टे पर तुरंत देने की पेशकश की. लेकिन वास्तव में केवल दो एअरबस और दो 737 विमान ही पट्टे पर दिए गए. इनमें से एक एअरबस तो दुर्घटनाग्रस्त हो गई.

ए-310: उम्मीदें पूरी न हुईं

एअर इंडिया ने या तो खरीदे जाने वाले विमान और यात्रियों की संख्या का अनुमान लगाने में गलती की या ए-310 के प्रस्ताव को यह जान कर मंजूर किया कि यह काम का नहीं

एअर इंडिया आज भी '707' विमानों की तरह लंबी दूरी तक उड़ान भरने वाले सामान्य क्षमता के विमानों की तलाश में है. अब इस तरह के दो नए विमानों की जांच-परख के लिए एअर इंडिया ने अपने छह विभागीय प्रमुखों की एक समिति गठित कर दी है. इन नए विमानों में चार इंजनों वाला ए-340 और तीन इंजनों वाला एमडी-11 विमान शामिल हैं. दोनों ही विमान 747 विमानों के मुकाबले कम यात्रियों को लंबी दूरी तक ले जाने में सक्षम हैं. एअर इंडिया के प्रबंध निदेशक राजन जेटली कहते हैं, "समिति यह फैसला करेगी कि 1990 में एअर इंडिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए कैसे विमानों की आवश्यकता होगी."

दूसरी ओर इंडियन एअरलाइंस की परेशानी पांच देशों की साझेदारी में 'इंटरनेशनल एअरो इंजन्स' द्वारा निर्मित वी-2500 इंजन को लेकर है. इंडियन एअरलाइंस में विमानों की कमी का नतीजा यह हुआ कि लगभग सभी हवाईअड्डों पर यात्रियों की लंबी कतारें लग गई. विमानों की कमी से यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है. इंडियन एअरलाइंस के हताश प्रबंध निदेशक पायस भी एअर इंडिया की तरह सोवियत संघ से पट्टे पर विमान मिल जाने की आस लगाए हैं. 150 सीटों वाले कुछ आइयू-154 विमान पट्टे पर लेने का एक प्रस्ताव भी विचाराधीन है. पायस के अनुसार इंडियन एअरलाइंस सोवियत अधिकारियों को पट्टे की कीमत कम करने के लिए मनाने की कोशिश में लगी है क्योंकि भारत में ईंधन की कीमत सोवियत संघ के मुकाबले साढ़े चार गुना अधिक है. लेकिन हालात के अनुसार इंडियन एअरलाइंस को अगले साल ए-320 विमानों के आ जाने तक क्षमता बढ़ाने के मामले में निराशा ही हाथ लगेगी. एक साल में 19 विमानों के मिल जाने से वह प्रतिदिन अतिरिक्त 3,000 यात्रियों को ढोने में सक्षम हो जाएगी. तब इंडियन एअरलाइंस को शुरुआत में यात्रियों की कमी का सामना करना पड़ेगा. यह बहुत देर तक भूखे रहने के बाद बेहद स्वादिष्ट भोजन मिल जाने जैसा ही होगा.

—रविंदर सिंह

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जब आँख लगें झपकने और हाथ-लगे रपटने...

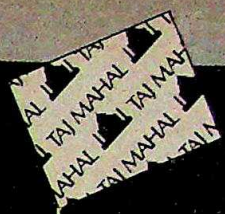

तो डिप लीजिये!

जब आपको झटपट एक कप मनपसन्द चाय की ज़रूरत पड़े, तब ताज महल टी बैग की सुविधा को अपनाइये. न कोई झंझट, न झमेला.

एक कप में एक ताज महल टी बैग रखिये. ताज़ा उबलता पानी डालिये. दो या तीन मिनट तक रखे रहिये. फिर टी बैग निकाल लीजिये. अपने स्वाद के अनुसार दूध और शक्कर मिलाइये. बस, हो गई आपकी चाय तैयार!

कप हो या चायदानी. दोनों में आसानी. (यदि आप चायदानी में चाय बना रहे हैं, तो 4 कप के लिये 3 टी बैग काफी हैं)

ताज महल
टी बैग

स्वाद व शान. बनाना आसान!

ब्रुक बॉंड पैकेट चाय.
हर पैकेट में एक-सी, भरोसेमंद क्वालिटी.

on, Haridwar

HTA 8615

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वकील आंदोलन

घर के चिराग से लगी आग

वकीलों के दोफाड़ होने से आंदोलन में नया मोड़

गरिमामय सुप्रीम कोर्ट की किस्मत में ये दिन भी देखने बदे थे. लगातार दो दिन तक उसके दरवाजे जनता ही नहीं, वकीलों तक के लिए बंद रहे. होली की एक हफ्ते की छुट्टियों के बाद जब अदालत खुली तो इसके बरामदों में इस कदर गहमागहमी थी मानो रेलवे प्लेटफार्म पर भीड़ घिर आई हो. मुख्य न्यायाधीश रघुनंदनस्वरूप पाठक की अदालत में जाने का प्रयास करते कुछ वरिष्ठ वकीलों के साथ भीड़ ने धक्कामुक्की की. पर न्यायमूर्ति पाठक परेशान से अपने कक्ष में लौट गए थे.

भीड़ में ज्यादातर दिल्ली की तीस हजारी अदालतों के वकील थे जो इस बात पर अड़ गए थे कि वरिष्ठ सहयोगियों को भी उनके साथ हड़ताल जारी रखनी चाहिए. मध्य जनवरी से वे उत्तर दिल्ली पुलिस की उपायुक्त किरण बेदी को बर्खास्त करने की मांग पर आंदोलन कर रहे हैं. 21 जनवरी को सैकड़ों वकीलों पर उस समय लाठी-चार्ज किया गया था जब वे एक वकील को हथकड़ी लगाए जाने का विरोध करने के लिए बेदी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे.

पिछले पखवाड़े के मध्य तक वकील उदार और कट्टर दो धड़ों में बंट गए. सुप्रीम कोर्ट के वकील सबसे उदार गुट में हैं और काम पर लौट आए हैं. उत्तरी राज्यों के अनेक हाईकोर्टों के वकील मध्यमार्गी गुट में होने के नाते जांच आयोग अधि-नियम के तहत जांच की अधिसूचना की मांग कर रहे हैं. ऐसी अधिसूचना जारी होने से फरवरी में बनाए गए दो सदस्यीय जांच आयोग को ज्यादा अधिकार मिल जाएंगे. एक आंदोलनकारी वकील के मुताबिक, "बिना अधिसूचना के तो यह महज तथ्य जमा करने वाली एक समिति भर है. इसके पास किसी को तलब करने का कोई अधिकार नहीं. बेदी तो इसके सामने पेश होने से ही इनकार कर सकती हैं."

तीस हजारी अदालतों के वकीलों ने सख्त रवैया अपनाया है इसलिए उनकी हड़ताल भी जारी है. वे अभी भी बेदी को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं जिसे गृहमंत्री बूटा सिंह पिछले पखवाड़े ही ठुकरा चुके हैं.

कट्टरपंथी वकील आस लगाए बैठे थे कि अधिसूचना जारी हो और बेदी की बर्खास्तगी का रास्ता साफ हो. मगर अधिसूचना नहीं निकली. कहना मुश्किल है कि कट्टरपंथियों का एक बड़ा तबका बेदी की बर्खास्तगी से कम पर राजी होगा या नहीं.

पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के अध्यक्ष और इंका सांसद मुरली भंडारे ने 6 फरवरी को सरकार के एक समझौता किया. इसमें जांच की अधि-सूचना जारी करने की बात तो थी पर उसने पहले बेदी की बर्खास्तगी का मामला शामिल नहीं था. आंदोलनकारी वकीलों ने समझौते को ठुकराकर भंडारे और तीस हजारी बार के नेताओं को निकाल बाहर किया.

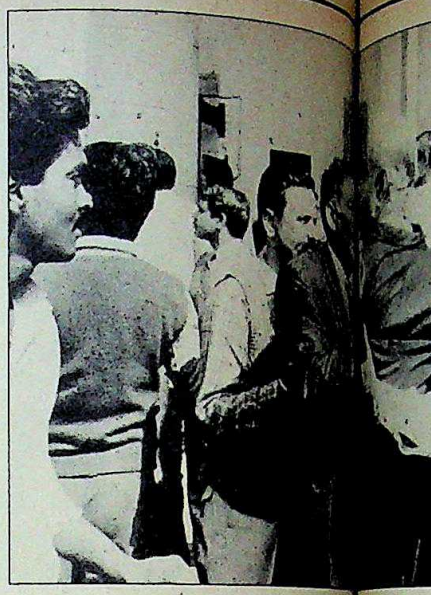

भंडारे से वकीलों की धक्कामुक्की

सुप्रीम कोर्ट के बंद दरवाजे

टाइम्स ऑफ इंडिया

अब मोर्चा गोविंद मुखोटी की अध्यक्षता में बनी एस 'संघर्ष समिति' ने संभाला. आंदोलन थमने लगा था कि 17 फरवरी को किराए के गुंडों ने तीस हजारी अदा-लतों के अहाते में वकीलों की कुछ कारों और दफ्तरों को तोड़-फोड़ डाला. माहौल फिर तूल पकड़ गया. सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हड़ताल में शामिल हो लिए. यह जल्द ही यह साफ हो गया कि उनमें से अधिकांश आंदोलन से हाथ धो लेना चाहते हैं. मुखोटी आड़े न आते तो हड़ताल पहले ही टूट जाती.

पांच दिन की जोरआजमाइश, ले-दे के बाद एटार्नी जनरल के. पारासरन ने एक ऐसे समझौते का प्रस्ताव रखा जिसके मुताबिक जांच

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

टाइम्स ऑफ इंडिया

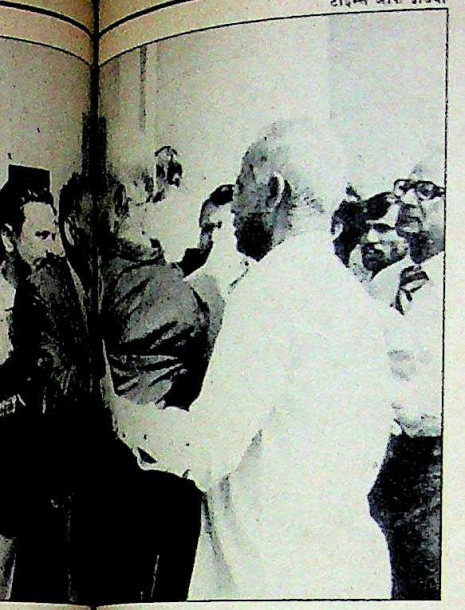

कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीशों से कराई जानी है (यह भी एक मांग थी). लेकिन उसी शाम दिल्ली के उपराज्यपाल ने जांच आयोग कानून के तहत नहीं बल्कि सरकारी आदेश के तहत जांच बिठाने की घोषणा कर दी. अब विवाद का मुद्दा यही बन गया. चार दिन बाद हड़ताल के मामले पर मतदान के समय जब कुछ अज्ञात शरारत-पसंद मतपेटियां छीनकर ले गए तो सुप्रीम कोर्ट के अधिकांश वकीलों ने आंदोलन से हाथ खींच लिए. मुखौटी ने घटना के विरोध में इस्तीफा दे दिया. उन्होंने माना कि शरारत-पसंदों में वकील भी थे.

अब आंदोलन की अगुआई तीस हजारी अदालतों में इंका और भाजपा के मिले-जुले तत्वों के हाथ में है. दोनों पार्टियां जनता के विरोध के डर से हाथ खींच लेना चाहती हैं.

मगर तीस हजारी बार के एक पूर्व पदाधिकारी कहते हैं, "अब सब कुछ भाजपा के लोग ही चला रहे हैं." भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष मदनलाल खुराना ने 17 फरवरी की घटना के बाद वकीलों के समर्थन में एक बयान जारी करके उस दिन के वाकयात के लिए केंद्रीय सूचना व प्रसारण-मंत्री हरिकिशनलाल भगत को जिम्मेदार ठहराया था. इस बयान के बाद भी लगता है आंदोलन में पार्टी की रुचि घटती जा रही है. एक वकील कहते भी हैं, "वकीलों के वोटों से मुवक्किलों के वोट कहीं ज्यादा हैं और कोई पार्टी उन्हें खोना नहीं चाहेगी."

ज्यादातर वकील एक हद से आगे सरकार के खिलाफ जाने को तैयार नहीं. क्योंकि 80 फीसदी मुकदमों में या तो खुद सरकार, उसकी एजेंसियां या सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां होती हैं. मुखौटी अपने आप को 'अराजनैतिक' मानते हैं पर उनका कहना है, "मुझ जैसे कुछ बेवकूफों को छोड़कर ज्यादा-तर वकील राजनैतिक महत्वाकांक्षाएं पाले हुए हैं और उनके वैसे संपर्क भी हैं."

एससीबीए के अध्यक्ष भंडारे पर भी कुछ वकील आरोप लगा चुके हैं कि वे निजी राजनैतिक फायदे के लिए बिक गए क्योंकि उनका राज्यसभा का कार्यकाल इसी महीने खत्म हो रहा है. पर भंडारे कहते हैं, "लोग बेसिर पैर की बातें करते हैं मैं वकीलों के लिए तुरंत कोई समाधान निकालना चाहता था."

उनकी बात में दम है. इस बीच सुप्रीम कोर्ट और तीस हजारी के वकीलों में मध्य-स्थता करने की कोशिश कर रहे तथा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट के.के. वेणुगोपाल पर भी निजी महत्वाकांक्षाओं के आरोप लगाए गए हैं. अटकलें हैं कि वे एटार्नी जनरल बनने का ख्वाब देख रहे हैं, या फिर एससी-बीए के अध्यक्ष बनना चाहते हैं. वेणुगोपाल इस सबका खंडन करते हैं, "अगर कोई किसी काम में हाथ डालता है तो लोग आरोप पहले ही लगाने लग जाते हैं."

बिडंबना ही है कि तीस हजारी के कट्टरपंथी वकील सुप्रीम कोर्ट के वकीलों पर हावी हो गए हैं. क्योंकि एससीबीए के नेताओं ने वोटों के चक्कर में पिछले कुछ वर्षों में बहुत से 'बाहरी लोगों' को इसका सदस्य बनवाया है. अब ये नेता आंदोलन को उदार बनाना चाहते हैं पर उन्हें अपने ही उन भस्मासुरों का सामना करना पड़ रहा है जो एससीबीए के सदस्यों के रूप में दरअसल तीस हजारी में काम करने वाले लोग हैं.

भंडारे और मुखौटी दोनों को ही समझ आ गया है कि वे एक ऐसे आंदोलन की अगुआई कर रहे थे जिसकी बागडोर निचली पंक्ति के लोगों के हाथ में है. तीस हजारी के वकील यह तो चाहते थे कि राष्ट्रीय स्तर के नेता उनके आगे रहें पर बेदी के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी उन्होंने कभी नहीं छोड़ी. जैसे ही उन्हें पता चलता कि फलां नेता कुछ करने लायक नहीं या करना नहीं चाहता, वे उसे फौरन नेतृत्व से हटा देते.

इस सारे प्रकरण में वकीलों की साख बिलकुल घट गई है. तीस हजारी के वकीलों ने अब तय किया है कि वे दो-दो, तीन-तीन के समूह में दिल्ली परिवहन निगम की बसों में सवार होकर जनसमर्थन जुटाने के लिए प्रचार करेंगे. पर अदालतें बंद होने से परेशान और वकीलों की राजनीति से चिढ़े लोगों के गुस्से का सामना कर पाना भी कोई आसान काम नहीं.

—डेविड देवदास

सुप्रीम कोर्ट

अपना हाथ जगन्नाथ

वकील बाहर आंदोलन कर रहे थे और मुवक्किल बेचारे मुकदमे की तारीख भुगताने की जोड़तोड़ में लगे हुए हैं. सुप्रीम कोर्ट में तो बहुतों ने खुद ही अपने मुकदमों की पैरवी भी की. कुछ परेशान लोगों को देखकर जहां दया उपजती थी, वहीं कइयों को हंसी-मजाक का मौका हाथ लगा था.

जो मुवक्किल अपना मुकदमा लड़ने खुद आए जजों ने नियम-कायदों से हटकर उनकी मदद की. कुछ एक ने तो बहुत अच्छी पैरवी भी की. इस पर कई लोग मजाक में पूछ बैठे, "क्या हमें वकीलों की जरूरत भी है."

सबसे बड़ी बाधा तो भाषा की थी. जज चाहते तो कार्यवाही अदालती भाषा अंग्रेजी में चलाते पर गैर-हिंदी इलाकों के जज भी मुवक्किलों से पूछ रहे थे, "क्या आप मामला पेश करना चाहते हैं या तारीख दे दें." कुछ मुवक्किल तो पंजाबी में भी बोले.

पर मुश्किलें तकनीकी कारणों से भी पेश आईं. तीन जजों की पीठ ने एक नौजवान से पूछा, "आपकी याचना क्या है." जवाब था, "माई लार्ड, इंसाफ कीजिए." जज बोले, "नहीं-नहीं, यह याचना नहीं. यह बताओ कि तुम हमसे क्या फैसला चाहते हो." "माई लार्ड, कानून को तो आप ही जानते हैं. अगर आप मदद नहीं करेंगे तो मैं मर जाऊंगा."

एक जज ने उसे डांटा, "यह अदालत से बात करने का तरीका नहीं." दूसरे ने समझाया, "अपनी याचिका के सातवें पेज को देखो. उसका अंतिम पैरा 'याचना' का है जिसके पढ़ने पर कोई सिर-पैर पता नहीं चलता. अब हम तुम्हें कुछ समय देते हैं. सोचो कि तुम हमसे क्या फैसला चाहते हो और फिर अपनी याचना दुबारा लिखकर दो." आखिर उस युवक को दूसरी तारीख देनी पड़ी ताकि उसकी याचिका बेहतर ढंग से पेश हो सके. उस समय तक निश्चय ही उसकी पैरवी के लिए एक वकील मौजूद होगा.

—डेविड देवदास

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

केरल

खुशहाली खात्मे की ओर

खाड़ी देशों में गए मलयाली तेजी से स्वदेश लौट रहे हैं

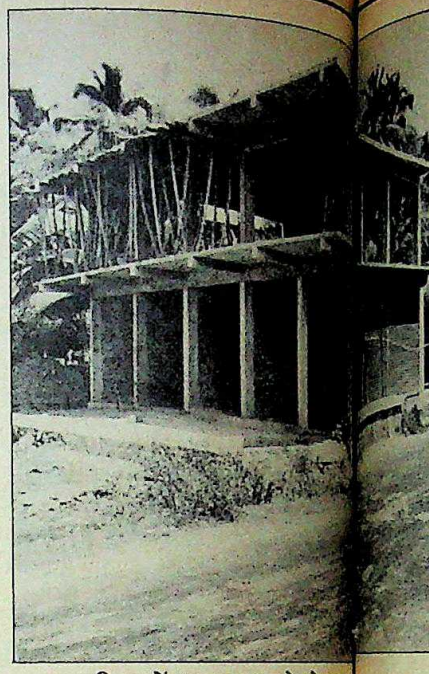

खुशहाल जिंदगी का दौर अब खत्म हो चला है. करीब एक दशक से पेट्रो डॉलर की बदौलत बढ़िया जिंदगी जी रहे केरल के लोगों का जीवन स्तर अब गिरने लगा है. इसके नतीजे बहुत भयावह हैं. तेल के दामों में गिरावट के साथ ही खाड़ी देशों में नौकरी करने गए हजारों मलयाली अब वापस लौट रहे हैं. नतीजतन जमीन की कीमतें गिरने लगी हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, मजदूरी की दरें घट गई हैं और यहां तक कि आत्महत्या की कई घटनाएं भी हुई हैं.

उपलब्ध आंकड़े भरोसेमंद तो नहीं हैं लेकिन इनसे इस प्रक्रिया का एक अंदाज तो लगता ही है. एक अधिकारी के अनुसार मोटे तौर पर 1984 में खाड़ी के देशों में काम करने वाले 18 लाख लोगों में से 1986 के दिसंबर तक ही 86,000 लोग लौट स्वदेश आए थे. खाड़ी के देशों की नौकरी के भरोसे जी रहे लोगों का जीवन भी अनिश्चित बना हुआ है.

सातवें दशक में नज़ारा कुछ और ही था. उस समय तेल की कीमतों में आए भारी उछाल के कारण खाड़ी देशों में मजदूरों की मांग अंधाधुंध बढ़ गई थी. बहुत ज्यादा कमाई से आकर्षित होकर लाखों की तादाद में मलयाली उधर दौड़ पड़े. मसलन तब एक राजमिस्त्री खाड़ी देशों में 10,000 रुपए मासिक से भी अधिक की कमाई की आशा कर सकता था.

आठवां दशक शुरू होते ही केरल में कई तरह के बदलाव दिखने लगे. गांव जाने वाले रास्तों में सुपर मार्केट, वातानुकूलित सिनेमाघर और आरामदेह होटल उग आए. छोटे सुघड़ घरों को गिराकर महलनुमा मकान बनाए जाने लगे. बाजारों से जो कुछ मिल सकता था, जैसे कार, दुपहिया गाड़ियां, रेफ्रीजरेटर और रंगीन टीवी सब कुछ पेट्रो डॉलर की आमद के साथ घर में आने लगा.

प्रायः सभी प्रमुख बैंकों ने इन छोटे 'खाड़ी' गांवों में अपनी शाखाएं खोल लीं और इनकी जमा रकम महीने भर में ही एक करोड़ रुपए की सीमा लांघ गई. एअर इंडिया के लिए त्रिवेंद्रम से खाड़ी के देशों का रूट सबसे फायदेमंद बन गया था. खाड़ी की ओर ऐसा रेला उमड़ पड़ा था कि पान की दुकानें भी ट्रेवल एजेंसियों में बदलीं.

लेकिन ऐसी लक्ष्मी कभी टिका नहीं करती. 1986 में एक बैरल तेल की कीमत 1981 के 35 डॉलर से घटकर 15 डॉलर पर आ गई. और इस गिरावट का नतीजा भी तुरंत दिखा. एक तरफ अरब देश में मालिक मजदूरों की छंटनी कर रहे थे तो दूसरी तरफ बचे हुए मजदूरों को कम वेतन और सुविधाओं पर काम करने को मजबूर कर रहे थे. कम होते रोजगार बाजार में श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे दूसरे देशों के मजदूरों ने मलयाली मजदूरों को पीछे छोड़ दिया.

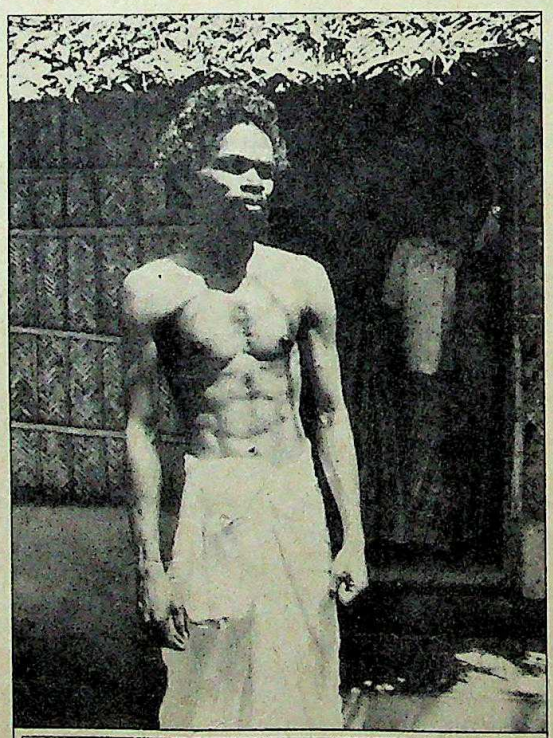

चावक्कड़ के प्रमुख मांस विक्रेता पुतुवीतिल अली दुकान बेचकर रियाद चले गए. कम मजदूरी पर काम करने की दौड़ में पिछड़ कर वे वापस आ गए हैं. अब उन पर 40,000 रुपए का कर्ज है

त्रिवेंद्रम में उतरने वाली एअर इंडिया की हरेक एअरबस यहीं टिके रहने वालों की भीड़ बढ़ाती जाती. मुख्यमंत्री ई.के. नयनार ने स्वीकार किया, "खाड़ी के देशों से लौटने वालों के आंकड़े खतरे की सीमा पार कर रहे हैं. उन्हें और राज्य को तंगहाली से बचाने के लिए हमें बहुत-कुछ करना पड़ेगा." वैसे इस समस्या से निबटने के लिए सरकार ने अब तक किसी योजना पर विचार नहीं किया है.

आत्महत्या की कभी-कभार होने वाली घटनाएं गहरी हताशा की सूचक हैं. खाड़ी से लौटे मलयालियों के एक संगठनों में से एक के प्रवक्ता [illegible] कुट्टी बताते हैं कि लौटने वालों में अधिकांश अर्द्ध-शिक्षित राजमिस्त्री हैं. कुछ ही महीने में वे कर्ज में डूब गए और चिड़चिड़े हो गए हैं. कुट्टी कहते हैं, "लौटने वालों में ज्यादातर को मेहनत-मजदूरी नहीं करना चाहते और इसके बाद तो इस स्थिति से छुटकारे का एकमात्र उपाय आत्महत्या ही बचता है.

केरल विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के डॉ. पी.आर. गोपीनाथ नायर ने खाड़ी जाने वालों का [illegible] में एक सर्वेक्षण किया. इस सर्वेक्षण

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सभी फोटो: श्याम टेकवानी

अधूरा पड़ा शापिंग कांप्लेक्स

कई मान्यताएं धराशायी हो जाती हैं. नायर कहते हैं कि खाड़ी जाने वालों के रंक से राजा बनने की कथाएं सर्वथा भ्रामक हैं. 42 प्रतिशत परिवारों का, जिनका कम-से-कम एक सदस्य खाड़ी कमाने गया, जीवन स्तर पहले से बेहतर नहीं हुआ.

त्रिचूर जिले के तीर्थस्थल गुरुवायूर के करीब 5 किलोमीटर दूर बसा चावक्कड़ (आबादी: 30,000) कस्बा इस संपन्नता के उतार का एक जीता-जागता उदाहरण है. एक समय तो इस गांव की करीब एक-तिहाई आबादी खाड़ी के देशों में चली गई थी. कभी चावक्कड़ के प्रमुख मांस विक्रेता रह चुके 40 वर्षीय पुतुवीतिल अली का मामला भी गांव के दूसरे सैकड़ों निवासियों की तरह ही है. 1982 में अली ने रियाद में 3000 रु. माहवारी और मुफ्त भोजन और आवास पर मिल रही रसोइए की नौकरी पाने के लिए 20,000 रुपए खर्च किए थे. लेकिन जब एक चीनी रसोइया उससे कम, 1600 रु. मासिक पर काम करने को तैयार हो गया तब अली की नौकरी चली गई. उसके बाद उसे 1200 रु. की तनख्वाह पर धोबी की नौकरी मिली और उसकी यह नौकरी उस समय छूट गई जब एक बांग्लादेशी ने 800 रु. में वही नौकरी कर ली. अब अली अपने ही धंधे में नौकर बन गया है. खाड़ी जाते समय वह इसे बेचकर गया था.

एक प्रमुख भवन निर्माता के अनुसार चावक्कड़ में 70 से ज्यादा मकान और बाजार अधबने पड़े हैं. अपने भाई के पांच बड़े कमरों के महलनुमा मकान के निर्माण की देखरेख कर रहे हमीद हाजी कहते हैं, "मेरे भाई ने पैसा भेजना बंद कर दिया है और मुझसे कहा है कि इसे बेचकर एक छोटा मकान बना लूं. पर यहां इस मकान को खरीदने वाला ही कोई नहीं है."

उत्तरी मालाबार के तेल्लीचेरी के धनी लोगों में से एक 52 वर्षीय अबु बाकर कई बड़ी मुश्किलों में फंस गए हैं. शहर के बीचोबीच एक अधबने शॉपिंग कांप्लेक्स में उनका 30 लाख रुपयाँ फंसा पड़ा है. खाड़ी में काम करने वाले जिन व्यक्तियों ने उनसे इस व्यावसायिक स्थल के बदले में पैसा जमा करने की पेशकश की थी अब वे मुकर गए.

तेल में एकाएक मंदी का असर केरल के फिल्म उद्योग पर भी पड़ा है. पिछले वर्षों में आप्रवासियों द्वारा हर साल कम-से-कम 30 मलयाली फिल्में बनाई जाती थीं. अब यह संख्या सालाना दो फिल्मों तक आ गई है. 1985 में 126 मलयाली फिल्मों के रिकार्ड से यह संख्या पिछले साल 78 पर उतर आई.

इसका असर इतना व्यापक है कि जो लोग केरल से बाहर नहीं गए वे भी इसका दंश महसूस कर रहे हैं. आठवें दशक के शुरू में हुनरमंद कारीगरों के बड़ी संख्या में बाहर चले जाने के कारण केरल में बढ़ई, बिजली मिस्त्री, नलसाज आदि कारीगरों ने अपनी दरें बढ़ा दी थीं. लेकिन हजारों बेरोजगार लोगों के लौट जाने से मजदूरी की दरों में आई कमी तनाव का कारण बन रही है.

हालांकि मध्यवर्गीय मलयाली लोगों के लिए एक अच्छी खबर भी है. आमदनी के साथ ही कुछ वस्तुओं के दाम भी कम हो रहे हैं. मसलन सबसे स्वादिष्ट मानी जाने वाली समुद्री मछली 'वेल्ला अवोली' (सरंगा) का दाम 50 रुपए किलो तक चढ़ गया था. अब यही मछली 35 रुपए प्रति किलो मिलने लगी है.

लेकिन कठिन दौर से गुजरने वाली राज्य सरकार के लिए यह राहत बहुत कम है. कुछ वर्षों पहले तक इस इलाके में खाड़ी के देशों से आने वाली रकम 450 करोड़ रुपए सालाना हुआ करती थी और इसमें हो रही कमी खतरनाक हो सकती है. इसके साथ ही बेरोजगारी की समस्या तो है ही.

हाल ही में जारी किए गए राज्य आर्थिक और सांख्यिकी ब्यूरो के एक सर्वेक्षण का निष्कर्ष है कि इनके पुनर्वास की समस्या सबसे कठिन है. लेकिन इस उलटी रफ्तार के बावजूद खाड़ी के देशों में नौकरी ढूंढ़ने पर आमादा लोगों का उत्साह अभी भी ठंडा नहीं पड़ा है. त्रिवेंद्रम में एअर इंडिया के एक प्रवक्ता कहते हैं, "हम पर अभी तक कोई विशेष असर नहीं पड़ा है. हमने प्रति हफ्ते 7 उड़ानों को बढ़ाकर अब 13 कर दिया है."

खाड़ी के एक दैनिक में काम करने वाले एक पत्रकार कहते हैं, "ईरान-इराक युद्ध खत्म होते ही तेल की कीमतों में एक और जोरदार उफान आएगा और मलयाली उससे फायदा उठाने में भी कामयाब रहेंगे." लेकिन इस सचाई पर अभी भी कोई यकीन करने को तैयार नहीं है कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी अब नहीं रही.

—श्रीधर पिल्लै

भाई के आलीशान मकान के निर्माण की देखरेख कर रहे हमीद हाजी को काम बंद कर देना पड़ा. भाई ने पैसा भेजना बंद कर दिया और अब वह चाहते हैं कि इसे बेचकर छोटा घर लिया जाए

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विश्वास के साथ सिफारिश

हर दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन

दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, दि
न प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, दिन
प्रतिदिन दिन प्रतिदिन, दिन प्र
तिदिन, न, दिन

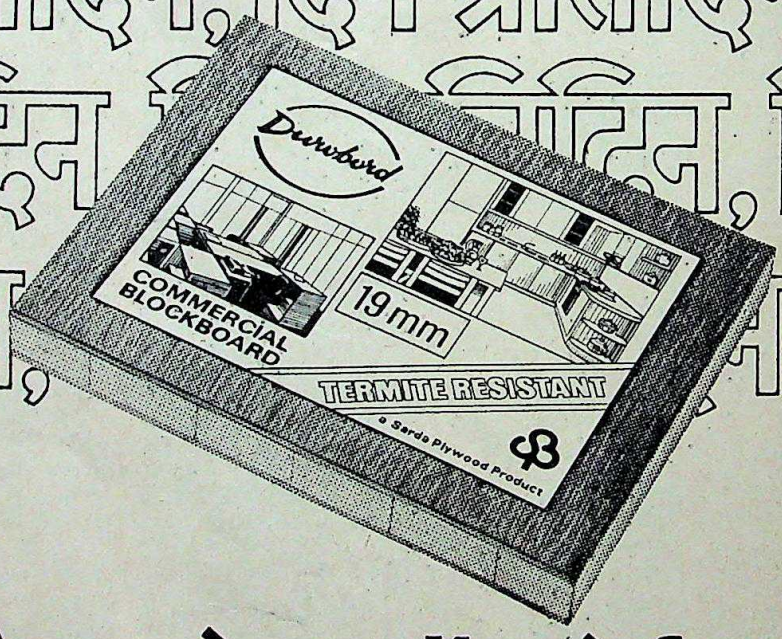

यह है ड्यूरो – ब्लॉकबोर्ड का हीरो

श्रेष्ठ इंटीरियर डेकोरेटर्स, उत्तम फर्नीचर निर्माता, निपुण कारीगर, अनुभवी विक्रेता व संतुष्ट उपभोक्ता सभी सहमत है कि क्वालिटी में ड्यूरोबोर्ड का जबाब नहीं यही वजह हैं कि ड्यूरोबोर्ड पिछले बीस वर्षों से ब्लॉकबोर्ड की दुनिया में सरताज है. इसीलिए तो उनकी सिफारिश, आपके नाम. हर दिन प्रतिदिन,दिन प्रतिदिन.....

सारदा प्लाइवुड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड

जैपुर (असम)

मुख्य विक्रय कार्यालय : १/७ डी ब्री गुप्ता रोड, नई दिल्ली ११० ०५५

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

खेसारी दाल

पंगु हो गई सरकार

नुकसानदेह दाल का अब मिलावट के लिए भी इस्तेमाल

विषैली खेसारी दाल की कीमतों में वृद्धि उत्तर-पूर्वी मध्य प्रदेश के उन हजारों खेतिहर और बंधुआ मजदूरों के लिए निश्चय ही एक खुशखबरी है, जो इसके सेवन से वर्षों से अपाहिज हो रहे हैं. कीमतें बढ़ जाने के कारण उनकी मजदूरी का भुगतान अब इस जानलेवा दाल के रूप में नहीं किया जाएगा.

देश के कुल खेसारी उत्पादन— पांच लाख टन— का दो तिहाई मध्य प्रदेश और बिहार में ही होता है. किसानों में खेसारी, मटरा और तिवरा नाम से परिचित दाल अपने हानिकारक प्रभावों के बावजूद यदि धड़ल्ले से उगाई जा रही है, तो इसकी वजह यह है कि इसकी फसल प्राकृतिक विपदाओं की मार सहने में पूरी तरह सक्षम है.

इस दाल का सेवन यदि तीन से छह महीने तक लगातार किया जाए तो शरीर पर बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ता है. इसमें मौजूद विषैले तत्व स्नायु तंत्र पर असर डालते हैं और पैरों की मांसपेशियों को लकवा मार जाता है. इसका कोई इलाज भी नहीं है. और इस रोग का आक्रमण अचानक ही होता है.

रीवा और उसके पड़ोसी जिलों में मजदूरी के रूप में खेसारी दाल बांटने की हानिकारक प्रथा बाजार के रुख के कारण अब बंद हो चुकी है. इस दाल की कीमत 400 प्रति क्विंटल तक पहुंच गई है. रीवा जिले के लौआ गांव के 63 वर्षीय सरपंच शोभानाथ पांडेय कहते हैं, "किसान बेवकूफ नहीं हैं, जो मजदूरी में मटरा दाल दे दें. मजदूर भी गेहूं लेना ज्यादा पसंद करते हैं." इस इलाके के मजदूर भी इसकी ताईद करते हैं. 'मटरा का चगुरा' (लैथाइरिज्म) बीमारी से पीड़ित मादो गांव के 60 वर्षीय वनवासी राजीशाल ने भी बताया कि "जबसे मटरा की कीमतें बढ़ी हैं, मालिकों ने इसे मजदूरी के रूप में देना बंद कर दिया है."

मुनाफे के लालच में व्यापारी इस दाल को शहरी उपभोक्ताओं को देने में भी नहीं हिचकिचा रहे. भोपाल में जहां अरहर की कीमत 15 रुपए प्रति किलो तक जा पहुंची है, बाजार खेसारी से पटा पड़ा है. शक्ल-सूरत में अरहर से मिलती-जुलती होने के कारण इसे अरहर की जगह या उसमें मिलाकर आसानी से बेचा जा रहा है. खेसारी दाल का इस्तेमाल करारे और स्वादिष्ट नमकीन भुजिया बनाने में भी किया जाता है.

खेसारी दाल की समस्या का 30 बरस तक अध्ययन करने वाले भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. महादेव प्रसाद द्विवेदी की एक रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश से खेसारी दाल का निर्यात पिछले तीन बरस में योजनाबद्ध तरीके से होने लगा है. उनका कहना है कि इस जहरीली दाल को अब और ज्यादा फायदेमंद रास्ता मिल गया है. वे चेतावनी देते हैं, "व्यावसायिक और राजनैतिक रूप से खेसारी के पैर पहले की तुलना में अब कहीं ज्यादा मजबूती से जम गए हैं और अब यह बड़े पैमाने पर दक्षिणी राज्यों को भेजी जा रही है."

फिर शहरी क्षेत्र लैथाइरिज्म के प्रकोप से अब तक कैसे बचे हुए हैं इसके तीन कारण हो सकते हैं— पहला यह कि यह दाल स्नायु तंत्र को तभी प्रभावित करती है, जब इसकी मात्रा व्यक्ति के कुल खाए गए भोजन का एक चौथाई से ज्यादा हो. दूसरा—बांग्ला देश में हाल में किए गए शोध से साबित हुआ है कि भोजन में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में लेते रहने से इस रोग से बचा जा सकता है. तीसरा—जैसा कि हैदराबाद स्थित पोषक आहार संस्थान का कहना है कि दक्षिणी राज्यों में लैथाइरिज्म को गलती से लकवा समझा जा सकता है.

तेजी से फैलते रोग से चिंतित होकर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने दालों में खेसारी की मिलावट की जांच का एक सरल तरीका सुझाया है: बिना साफ की गई खेसारी में 50 मिलीग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का घोल मिलाएं और लगभग पचास मिनट तक इसे हिलाते रहें. यदि दाल में खेसारी की मिलावट है तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा. खेसारी की मिलावट जांचने का यह तरीका भले ही सरल हो, इसका निवारण बेहद कठिन साबित हुआ है. यदि इस रोग ने शहरी जनता को भी अपनी लपेट में लिया तो उसकी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश और बिहार सरकार के सिर ही होगी क्योंकि इन दो राज्यों और पश्चिमी बंगाल के अलावा पूरे देश में खाद्य अपमिश्रण नियमों के तहत इस दाल की बिक्री और वितरण पर पाबंदी लगी हुई है. उत्तर प्रदेश सरकार ने तो इसकी खेती पर भी प्रतिबंध लगाया हुआ है.

विषैली खेसारी दाल के कारण रीवा के 25 हजार लोग लकवे जैसी बीमारी से पीड़ित हैं, फिर भी सरकार विचलित नहीं हुई. यह दाल दूसरे शहरों में भी पहुंच गई है

प्रमोद पुष्करणा

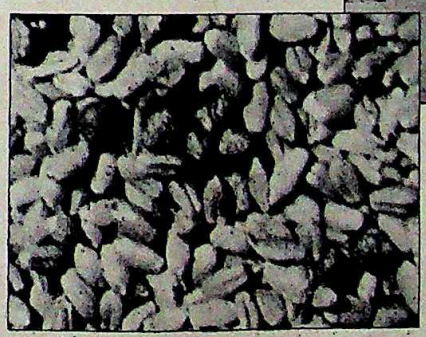

खेसारी की मार से पीड़ित मजदूर, और (बाएं) खेसारी दाल: धीमा जहर

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इसके विपरीत मध्य प्रदेश सरकार ने तो राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रामचंद्र सिंहदेव की अध्यक्षता में गठित समिति के सुझावों पर अमल करने से ही इनकार कर दिया. हालांकि इस समिति का गठन खुद राज्य सरकार ने ही किया था. 1982 में बनी समिति ने अक्तूबर 1985 में अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 'खाद्य अपमिश्रण निरोधक कानून' के अंतर्गत खाद्य पद्यार्थों में खेसारी दाल के मिश्रण पर रोक और मंडियों में इसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए. समिति का यह भी सुझाव था कि स्वास्थ्य विभाग चेचक की तरह इस रोग को भी ऐसा रोग घोषित करे जिसकी सूचना सरकार तक पहुंचाना अनिवार्य हो.

इस दिशा में राज्य सरकार ने अब तक बस एक ही कदम उठाया है. एक स्वैच्छिक संस्था द्वारा दायर किए गए एक मुकदमे में 1982 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने मजदूरी के रूप में खेसारी दाल दिए जाने पर पाबंदी लगा दी है. अब बाजार के रुख के कारण ऐसा पहले ही हो चुका है. पर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट से किए दो वायदों—खेसारी दाल की बुवाई पर पाबंदी और उपलब्ध दाल का जहरीलापन दूर करने के लिए दो संयंत्रों की स्थापना— को पूरा करने में अब तक सरासर नाकाम रही है.

'मटरा का चंगुरा रोग' यानी लैथाइरिज़्म लगभग एक दशक से बहस का मुद्दा बना हुआ है (इस बीमारी में पैरों को जैसे फालिज़ मार जाता है). लगभग सभी विशेषज्ञ एकमत हैं कि इस रोग का एकमात्र समाधान यही है कि खेसारी दाल की बुवाई पर ही पाबंदी लगा दी जाए. लेकिन शायद राज्य सरकार में राजनैतिक इच्छा की भारी कमी है. मिसाल के तौर पर 1963 में सरकार ने थोड़े दिनों के लिए इसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था. लेकिन दाल उत्पादकों की लॉबी के दबाव के कारण जल्दी ही उसे पाबंदी हटानी पड़ी. डॉ. द्विवेदी का कहना है कि यदि इस रोग की लपेट में गरीब के बजाय संपन्न वर्ग के लोग आते तब शायद प्रशासन की आंखें खुलतीं. 1985 में किए एक सर्वेक्षण के अनुसार रीवा जिले में ही तकरीबन 25,000 लोग—जनसंख्या का लगभग 4 प्रतिशत—लैथाइरिज़्म ग्रस्त थे. लेकिन ये आंकड़े राज्य सरकार को जरा भी विचलित नहीं कर पाए. लगता है खेसारी दाल ने या फिर इसके उत्पादकों की लॉबी ने मध्य प्रदेश सरकार को भी पंगु कर रखा है.

—नरेंद्र कुमार सिंह, रीवा में

दिल्ली

जुदा किए शरीर

सर्जरी के क्षेत्र में कमाल

पिछले पखवाड़े जब छोटी और मोटी ने जिंदगी में पहली बार अलग-अलग लेटकर अपनी बोतलों से भोजन लिया तब वहां मौजूद तीन डॉक्टरों के चेहरों पर खुशी की चमक कौंध उठी. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के तीन सर्जनों समेत 13 डॉक्टरों ने लगातार 14 घंटे तक ऑपरेशन करके छाती के निचले हिस्सों में एक दूसरे से जुड़ी 6 मास की बच्चियों को अलग-अलग कर दिया.

प्रमोद पुष्करणा

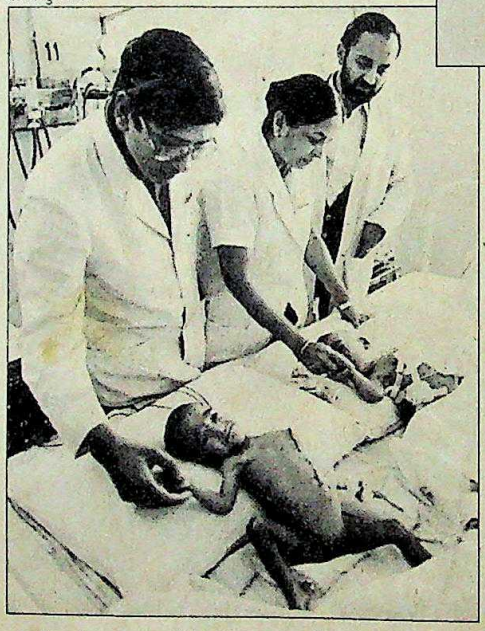

पिछले अगस्त में जब इन बच्चियों के दादा उ.प्र. के अल्मोड़ा जिले के नानौली गांव से उन्हें लेकर बालरोग विभागाध्यक्षा प्रो. मृदुला रोहतगी के पास आए उस समय वे मात्र 3 किलो वजन की थीं. प्रो. रोहतगी के शब्दों में, "हमारे लिए यह एक चुनौती थी जिसे हमने स्वीकार कर लिया." इस चुनौती का जवाब देने में विभाग के डॉ. डी.के. गुप्ता और डॉ. वी. भटनागर ने बखूबी उनका साथ निभाया.

वैज्ञानिक मानते हैं कि दो शुक्राणुओं से निषेचित डिंब यदि पूरी तरह विभाजित नहीं हो पाता तो जोड़ के स्थान पर दोनों भ्रूण भी जुड़ जाते हैं. इस जोड़ के कारण यदि दोनों भ्रूणों के दिल, फेफड़े या जिगर साझे हो जाएं तो जन्म के बाद बच्चों के बचने की संभावनाएं क्षीण हो जाती हैं.

सौभाग्य से इस मामले में ऐसी पेचीदगियां नहीं निकलीं. डॉक्टरों ने बच्चियों के 8 किलो तक बढ़ने तक प्रतीक्षा करने का फैसला किया ताकि वे सर्जरी सहन करने योग्य हो जाएं. इस दौरान यह देखा गया कि मोटी तो शांत और संतुष्ट रहती है लेकिन समय पर दूध पीने के बावजूद छोटी दूध के लिए रोती रहती है. इससे डॉक्टरों को

पीटीआई

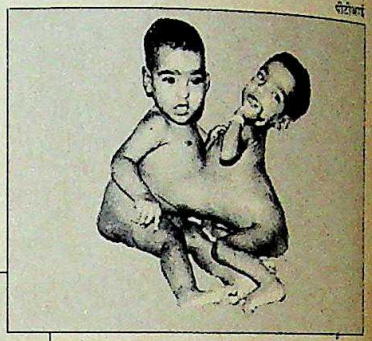

ऑपरेशन से पहले (ऊपर) और बाद में: बड़ी कामयाबी

शक हुआ कि संभवतया छोटी के भोजन का कुछ हिस्सा मोटी के शरीर में जा रहा है. बाद में जांच करने पर पता चला कि दोनों बच्चियों में छोटी आंत का एक भाग साझा था और दोनों की पित्त वाहक नलियां जुड़कर छोटी आंत में जाकर गिर रही थीं. सर्जरी के दौरान इन मूल अंगों को छोटी के शरीर में रहने दिया गया और मोटी के लिए पित्त वाहन की कृत्रिम व्यवस्था की गई.

डॉक्टरों के पूरे दल ने सर्जरी से पहले इसकी दो बार पूरी रिहर्सल की. रोहतगी बताती हैं, "रिहर्सल के दौरान ही तय कर लिया गया था कि बच्चियों को किस मुद्रा में लिटाया जाएगा और किसके जिम्मे क्या काम होगा."

इस मामले में रोहतगी और उनके सहयोगियों की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि बहुत थोड़ी संभावनाएं होने के बावजूद वे दोनों को ठीक तरह से अलग करने और उनकी जान बचाने में सफल रहे. यदि इस सफलता को भारत में तकनीक और विज्ञान की प्रगति का एक प्रमाण माना जाए तो इससे जुड़ा एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी रहा कि नानौली गांव में बच्चियों के परिवार को भेजा गया तार ऑपरेशन के पांच दिन बाद तक भी नहीं पहुंच पाया था.

—विजय जोशी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गुजरात

करघे से किस्मत चमकी

गलीचा बुनाई से वनवासियों का जीवन स्तर सुधार पर

अब उसे कभी जंगली कंदमूल या चूहे खाने की जरूरत नहीं. दो वर्ष पहले ये चीजें मानसून के दिनों में पाली दिवला के भोजन का अभिन्न अंग हुआ करती थीं. तब वह बेरोजगार थी. लेकिन अब गुजरात की यह अनपढ़ वनवासी महिला एक गलीचा बुनाई केंद्र में बतौर प्रशिक्षक छह हजार रुपए प्रतिमाह कमा लेती है. दक्षिणी गुजरात के जंगलों में वनवासियों को रोजगार मुहैया कराने की एक योजना ने दिवली जैसे 3000 वनवासियों के जीवन में भारी परिवर्तन ला दिया है. ये सभी वनवासी देश के एक सबसे पिछड़े तालुके धरमपुर के रहने वाले हैं.

आठ साल पहले तक इस क्षेत्र में गलीचा बुनाई की कोई परंपरा नहीं थी. पर अब सूरत, बलसाड और इस सरीखे वनवासी जिलों से अमेरिका व पश्चिम जर्मनी सहित कई देशों को गलीचे निर्यात किए जाते हैं. स्वयंसेवी संस्था गुजरात खेत विकास परिषद (जीकेवीपी) ने यह असंभव को संभव कर दिया है. उसने इस इलाके में गलीचा बुनाई की 35 इकाइयां स्थापित की हैं. यह तो शुरुआत भर है. जीकेवीपी की गलीचा शाखा के 45 वर्षीय अध्यक्ष शंकरभाई पटेल कहते हैं, "केंद्र और राज्य सरकार से ज्यादा सहायता मिले तो हम बहुमुखी विकास कर सकते हैं." मुख्यमंत्री अमरसिंह चौधरी 1978 में इस विधायक हुआ करते थे तो उन्होंने प्यारा तालुका गलीचा सहकारी समिति बनाई थी. लेकिन उसका काम दरअसल 1980 में समिति के 33 वर्षीय सचिव हितेंद्र उपाध्याय ने ही शुरू किया. पहली गलीचा इकाई व्यारा के नजदीक बनाई गई. अब चौधरी के स्थान पर शंकरभाई पटेल को समिति का अध्यक्ष बनाया गया था. योजना को शुरुआती और सबसे महत्वपूर्ण सहयोग गुजरात के कुटीर उद्योग निदेशालय से मिला. निदेशालय स्वयंसेवी संस्थाओं को 50 लोगों के एक वर्ष के प्रशिक्षण के लिए 1.85 लाख रुपए देता है (इसमें दस करघों की लागत भी शामिल है). शुरू में प्रशिक्षक जयपुर से बुलाए गए.

प्रमुख समस्या तो थी तैयार 200 वर्ग फीट गलीचों को बेचने की. जगह-जगह खरीदार ढूंढ़ते उपाध्याय को आखिर जयपुर का एक व्यापारी मिला जो गलीचों की तिजारत का इच्छुक था. अब यह व्यापारी न सिर्फ गलीचों का निर्यात करता है बल्कि उनके लिए कच्चा माल भी मुहैया कराता है. यह कच्चा माल जीकेवीपी के जरिये 35 इकाइयों को कंट्रोल करने वाली पांच वनवासी सहकारी समितियों को भेजा जाता है. जयपुर के व्यापारी को हालांकि 15,000 वर्ग फीट गलीचे ही हर महीने सप्लाई किए जाते हैं पर वह तो इससे तीन गुना माल भी खरीदने को तैयार है. समितियों के लिए तो यह और भी फायदे का सौदा है. चूंकि उन्हें कच्चा माल नहीं खरीदना पड़ता इसलिए पूंजी भी कम ही लगानी पड़ती है—सिर्फ 3.5 लाख रुपए. गलीचा बुनने की एक इकाई को 10 करघे, झाड़-फूस की एक झोंपड़ी और कुछ कारीगरों की जरूरत होती है. बुनकर 14 रुपए प्रतिदिन कमाते हैं जबकि न्यूनतम मजदूरी 11 रुपए ही है. प्रशिक्षक भी एक हजार से 1800 रुपए प्रतिमाह कमा लेते हैं.

बलसाड जिले के बदहाल धरमपुर तालुके में यह सफलता तो और भी साफ दिखती है. अभी यहां कुल पांच इकाइयां हैं. लेकिन जीकेवीपी रोजगार मुहैया कराकर ही संतुष्ट नहीं. वह इस बात का ध्यान भी रखती है कि बुनकरों में 60 फीसदी से ज्यादा स्त्रियां ही हों. उपाध्याय बताते हैं, "ऐसा इसलिए किया जाता है कि मजदूरी में मिलने वाला पैसा शराब में न बहा दिया जाए. वनवासियों को शराब की आदत जो है." इससे महाराष्ट्र के नासिक जिले के वनवासी भी प्रभावित हुए हैं. हाल ही में उन्होंने जीकेवीपी से ऐसी ही योजना उनके लिए भी तैयार करने का आग्रह किया.

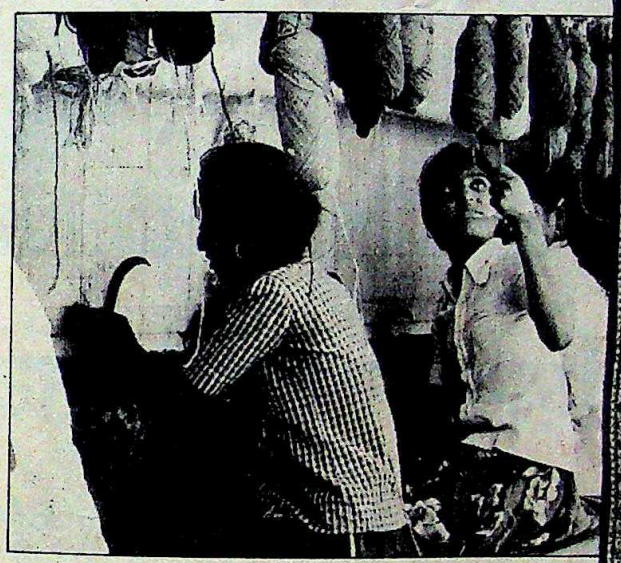

धरमपुर में करघे पर गलीचे की बुनाई, और तैयार गलीचा

हालांकि इस सफलता का ज्यादातर श्रेय पटेल और उपाध्याय को ही है, पर जीकेजीकेवीपी के अध्यक्ष और राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग के अध्यक्ष झीनाभाई दरजी ने भी इस उद्योग को सफल बनाने के लिए अपने संपर्कों का जमकर इस्तेमाल किया.

इस साल के अंत तक जीकेवीपी की 50 और इकाइयां स्थापित करने की योजना है. किसी और संस्था के लिए यह चाहे ऊंची उड़ान लगे लेकिन जीकेवीपी की सफलता को देखते हुए संदेह की कोई गुंजाइश नहीं.

—उदय माहूरकर, धरमपुर और व्यारा में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

राजनैतिक नेताओं के नाम पर खोले गए दो कॉलेज: भारी दबदबा

बिहार

उच्च शिक्षा की दुकानदारी

राजनेताओं की कमाई का साधन बने निजी कॉलेज

वैसे तो भागवत झा आज़ाद सरकार के सामने कठिन कामों की लंबी फेहरिस्त है पर उच्च शिक्षा की तरह कुछ महकमे उसके लिए खासे मुश्किल दिखाई देते हैं. हालांकि आज़ाद ने कहा कि वे शिक्षा के क्षेत्र में फैला भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कटिबद्ध हैं पर यह वायदा पूरा करना उनके लिए काफी मुश्किल साबित होगा, क्योंकि बिहार में स्वयंभू निजी कॉलेजों के प्रबंध मंडलों से कुछ मंत्रियों सहित करीब 200 विधायक जुड़े हैं.

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में फैली गड़बड़ी अब उजागर होने लगी है. बिंदेश्वरी दुबे सरकार के कुछ फैसलों पर मानव संसाधन विकास-मंत्री नागेंद्र झा ने पुनर्विचार का आदेश दिया है. अपने तीन साल के राज में दुबे प्रशासन ने विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबद्ध 36 कॉलेजों को अंगीभूत कॉलेजों का दर्जा दिए जाने का आदेश दिया था. इससे ये कॉलेज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राज्य सरकार से भारी-भरकम अनुदान राशि पाने के काबिल हो गए. लेकिन झा ने जब पाया कि कॉलेजों को अंगीभूत होने का दर्जा देने में नियम ताक पर रख दिए गए थे तो उन्होंने पुनर्विचार के आदेश जारी कर दिए.

इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है. बिहार का कॉलेज 'उद्योग' लंबे समय से फल-फूल रहा है और आज़ाद के विरोधियों के अलावा दूसरे भी मानते हैं कि वे इस पर अंकुश लगाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे.

इस धंधे का तरीका बड़ा आसान है और वर्षों से आजमाया जा रहा है. किसी विश्वविद्यालय से मान्यता हासिल कर लेने के बाद कोई भी नेता या व्यवसायी कॉलेज शुरू कर देता है. 15,000 या 20,000 रुपए (कभी-कभी यह रकम बहुत ज्यादा भी होती है) के 'डोनेशन' के एवज में वह एम.ए. या एम.एस.सी. कर चुके बेरोजगारों को नौकरी देने का लालच देता है.

प्रबंधक ऐसे बेरोजगारों से वायदा करते हैं कि पहले कुछ सालों तक तो उन्हें वेतन के नाम पर एक प्रतीकात्मक रकम ही मिलेगी लेकिन कॉलेज को अंगीभूत का दर्जा मिलते ही जिंदगी भर के लिए उनकी नौकरी पक्की हो जाएगी. हालांकि इस प्रक्रिया में कई साल लग जाते हैं. पढ़े-लिखे बेरोजगार भविष्य के इसी झांसे के कारण नेताओं अच्छी-खासी रकम देने को प्रेरित होते हैं उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से का वेतन कभी नहीं मिल पाता.

फिलहाल करीब 6,000 अध्यापक 12,000 शिक्षेतर कर्मचारी बगैर नि पत्र या वेतन के 187 संबद्ध कॉलेजों में कर रहे हैं. ये आंकड़े 'बिहार-सज

जमींदारी उन्मूलन के बाद जमीदारों ने हदबंदी से ज्यादा जमीन को अधिग्रहण से बचाने के लिए शिक्षा संस्थान खोलने का अच्छा उपाय पा लिया था

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

...ी महाविद्यालय शिक्षक-शिक्षेतर कर्मचारी ...संघ' के अध्यक्ष सियाराम शर्मा के हैं. ...में से कई 'भाग्यशाली' लोग फिलहाल ...ति माह 250 से 450 रुपए नाममात्र का ...तन पा रहे हैं.

आश्चर्य नहीं कि इनमें से ज्यादातर लोग ...री के कारण ही नौकरी 'खरीदने' को ...ध्य हुए हैं. अपनी दुर्दशा की ओर सरकार ...ध्यान आकर्षित करने के लिए महासंघ ने ...बर में पटना में एक विशाल रैली की थी. ...ना के एक निजी कॉलेज में रसायनशास्त्र ...ग की विभागाध्यक्ष 35 वर्षीय ...ता देवी की मौत इसका तात्कालिक कारण ...ी थी. चिंता देवी ने बच्चों का भरण-...ण करने में अपनी असमर्थता के कारण दो ...चों और खुद को जहर देकर खत्म कर ...ला था. पटना के दीघा इलाके के कांति ...र महिला महाविद्यालय से उन्हें पिछले ...ाह मालों से वेतन नहीं मिला था.

...बाजों और राजनैतिक नेताओं का यह ...जोड़ लंबे समय से चला आ रहा है. ...51 तक तो अधिकांश निजी कॉलेजों की ...ना लोकोपकारी लोगों ने की थी. लेकिन ...दारी उन्मूलन के बाद जमींदारों ने ...ी हदबंदी से ज्यादा ...ीन अधिग्रहण से बचाने ...लिए शिक्षा संस्थाएं खोलने ...ा अच्छा उपाय पा लिया. ...ने चुनावी राजनीति ने ...ी अपनी भूमिका निभाई.

हालांकि पांचवें दशक ...क एक साल में सिर्फ एक ...ा दो निजी कॉलेजों को ही ...ंगीभूत कॉलेज का दर्जा ...ल पाता था. लेकिन सातवें ...क तक अंगीभूत दर्जा पाने के लिए राज्य ...कार पर निजी कॉलेजों के प्रबंधकों का ...ाव बेतरह बढ़ गया. मसलन जनता पार्टी ...ासन के दौरान 1978 में 138 संबद्ध ...लेजों को अंगीभूत इकाई बनाया गया. ...किन 1980 में जब इंका के जगन्नाथ मिश्र ...ख्यमंत्री बने तो अध्यापकों का शोषण खत्म ...ने की दलील देकर 137 दूसरे कॉलेजों ...ो भी उपकृत कर दिया गया.

लेकिन निजी कॉलेजों का खर्च उठाने की ...रकार की भी अपनी सीमाएं थीं क्योंकि ...ंगीभूत इकाई का दर्जा देने के बाद सरकार ...ो कॉलेज का आधा खर्च उठाना पड़ता है. ...ज्य सरकार को पहले भी संबद्ध कॉलेजों को ...ाशिक सहायता देनी पड़ती थी. जगन्नाथ ...ध में चूंकि निजी कॉलेजों को विश्व-...द्यालय की संबद्धता देने पर रोक लगाने की ...जनैतिक इच्छाशक्ति नहीं थी इसलिए 1982 में उन्होंने बीच का रास्ता अपनाया. उन्होंने कहा कि निजी कॉलेजों को तो खुलने दिया जाएगा लेकिन राज्य सरकार सिर्फ अंगीभूत कॉलेजों को ही सहायता देगी. इस तरह 'गैर-सहायताप्राप्त संबद्ध कॉलेज' बने.

मिश्र के उत्तराधिकारी, दिवंगत चंद्रशेखर सिंह ने तो और भी जोरदार कदम उठाया. उन्होंने गैर-सहायताप्राप्त स्नातकोत्तर विभागों को खोलने की मंजूरी दे दी. उधर इनके अध्यापक दिहाड़ी पर ही काम करते रहे. दुबे ने भी इस गड़बड़झाले में अपना योगदान किया और 1985 से 1987 तक 36 और कॉलेजों को अंगीभूत इकाई बना दिया. कुछ प्रबंधकों को तो कॉलेज विकास के मद में सरकारी अनुदान भी दिया गया.

प्रदर्शन करते अध्यापक और (इनसेट में) सियाराम शर्मा: वेतन नदारद

हजारों अध्यापकों ने इसी उम्मीद में निजी कॉलेजों के मालिकों को चंदा दिया कि भविष्य में उन्हें अच्छे वेतन वाली नौकरियां मिल जाएंगी

आने वाले वर्षों में यह स्थिति और गंभीर बन सकती है. अंगीभूत दर्जा प्राप्त करने के इच्छुक 187 कॉलेजों के अलावा 150 दूसरी शिक्षा संस्थाएं भी विश्वविद्यालयों से संबद्धता प्राप्त करने का इंतजार कर रही हैं. जहां अध्यापकों को नौकरी खरीदनी पड़ती है उन कॉलेजों के 2.83 लाख छात्रों को कैसी शिक्षा मिलती होगी, सहज अनुमान्य है.

प्रशासन इस स्थिति से भलीभांति परिचित है. 1980 में बने विश्वविद्यालय जांच आयोग के प्रमुख, शिक्षाविद डॉ. वी.एस. झा ने 1983 में पेश की गई अपनी अंतरिम रिपोर्ट में इस व्यवस्था की जमकर खिंचाई की थी. रिपोर्ट में एक जगह कहा गया, "कहा जाता है कि यदि आप नेता हैं या हंगामा खड़ा करने की औकात रखते हैं तो बिहार में नया कॉलेज खोलना सबसे फायदे का धंधा है."

झा और आजाद की बेचैनी की कुछ और वजहें भी हैं. दुबे के कार्यकाल में बनाई गई तीन सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने इस साल के शुरू में कुछ सनसनीखेज रहस्योद्घाटन किए. इनमें से एक यह है कि संबद्ध कॉलेजों में जानबूझकर ज्यादा स्टाफ भर लिया गया ताकि कॉलेज अंगीभूत इकाई बन जाने के बाद स्टाफ का वेतन सरकार को देना पड़े. इस समिति के प्रधान थे अंतर-विश्वविद्यालय परिषद बिहार के अध्यक्ष आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा. समिति को यह भी पता लगा कि कुछ मामलों में तो कॉलेजों को अंगीभूत दर्जा मिलने के बाद नियुक्तियां की गईं.

इस समय राज्य में मौजूदा नेताओं के नाम वाले कॉलेजों की भरमार है. इसमें रिकार्ड बनाया है इंका के असरदार यादव नेता रामलखन सिंह यादव ने. उनके नाम से बिहार भर में 57 कॉलेज और दूसरे संस्थान चल रहे हैं. कुछ कॉलेज तो जाने-माने नेताओं ने खुद ही कायम किए हैं.

जिन नेताओं के नाम से कॉलेज चल रहे हैं उनकी सूची लंबी भी है और असरदार भी. इनमें पूर्व मुख्यमंत्री विंदेश्वरी दुबे, असम के पूर्व राज्यपाल भीष्मनारायण सिंह, केंद्रीय शिक्षा और सांस्कृतिक कार्य राज्यमंत्री ललितेश्वर प्रसाद शाही, पूर्व विदेशमंत्री बलिराम भगत, पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र, दिवंगत चंद्रशेखर सिंह और कर्पूरी ठाकुर,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मेरी आवश्यकताएं बिल्कुल सादा, पर मेरा काम बहुत ज़्यादा।

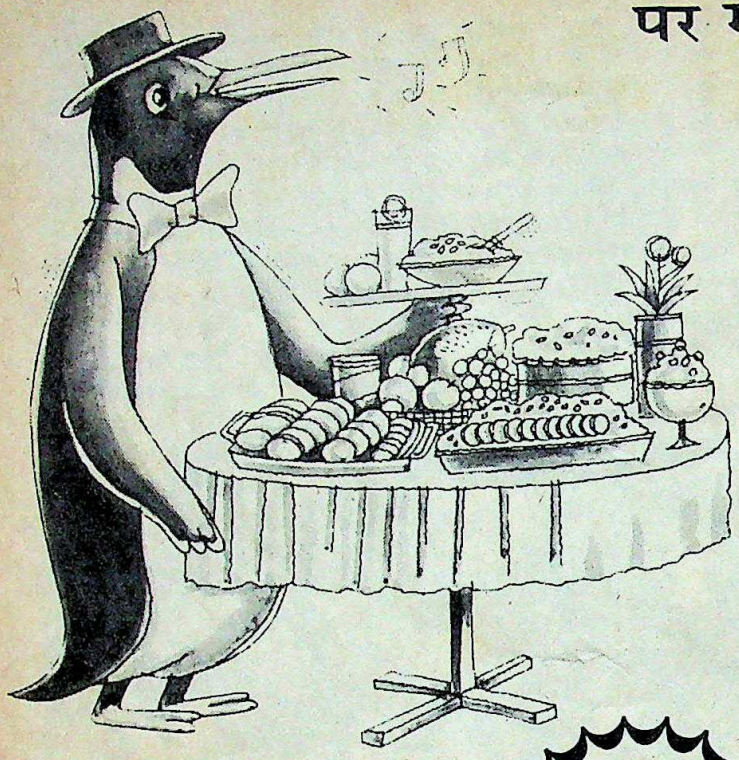

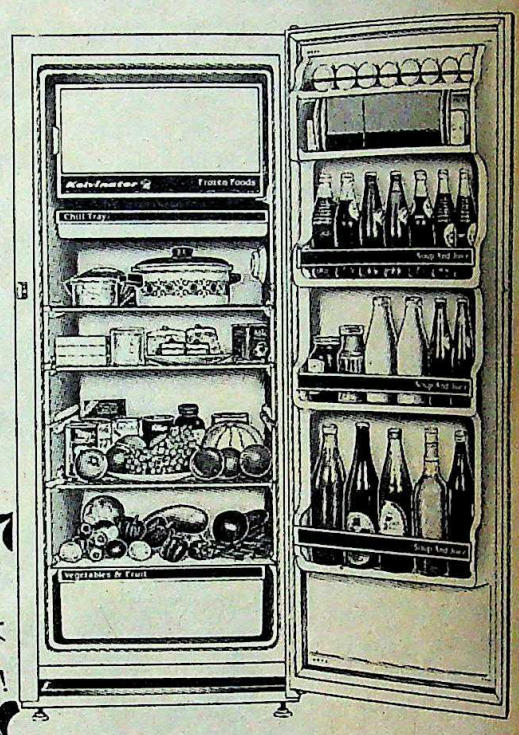

बिजली के उतार-चढ़ाव सहन करने वाला अन्दरुनी प्रोटेक्टर !

वोल्टेज स्टेबिलाइज़र की कोई आवश्यकता नहीं!

नर सम्राट पेंगविन, अपने वंश हेतु, अण्ड-सेवन अवधि में अति प्रतिकूल मौसम परिस्थितियां झेलता है। अपनी त्वचा के अन्दर जमां चर्बी की परत के सहारे ही जीवित रहता है। बर्फ़ की तीव्र आंधी में भी सीधा खड़ा रहता है ताकि अण्डे को कम तापमान के कारण हानि न पहुंचे। जब अण्डे से बच्चा निकलता है तो उसे अपने पिता की त्वचा के नीचे जमां चर्बी का ही आहार दिया जाता है।

संदर्भ : रीडर्स डाइजैस्ट की एन्टार्कटिका तथा बर्ड्स ऑफ़ दि वर्ल्ड.
लेखक ऑलिवर एल. ऑस्टिन जूनियर प्रकाशक : ऑप्टिमम

केल्विनेटर रेफ़्रिजरेटर कुशलतापूर्वक कार्य करता है। बिना थके। बिना रुके। वर्षों आपकी विश्वसनीय सेवा करता है। बहुत ही कम बिजली की खपत द्वारा।

इसके कार्य-कौशल का श्रेय पात्र है इसका विश्वविख्यात 'पावर-सेवर' कम्प्रैसर। अत्यंत किफ़ायती, न्यूनतम बिजली की खपत। उच्च व्यापक तापमान में भी तेजी से ठंडा करता है तथा विस्तृत वोल्टेज उतार-चढ़ाव सहन करता है।

विशेष खूबियाँ :

* पूर्ण इन्सूलेशन, कैबिनेट तापमान को बेहतर बनाती है।
* मज़बूत ए बी एस लाइनर।
* सर्विस में विश्वसनीय।
* बिजली की खपत में अत्यंत किफ़ायती।
* विशाल स्टोरेज क्षमता।
* टिकाऊ। * सुन्दर एवं सुदृढ़।
* विभिन्न बाहरी फ़िनिश तथा मनभावन अन्दरूनी रंगों में उपलब्ध।
* अनेक मॉडल।

केल्विनेटर
रेफ़्रिजरेटर
"इसकी ठण्डक...बेमिसाल!"

बिक्री एवं सर्विस के लिए :
एक्सपो मशीनरी लिमिटेड
प्रगति टावर, 26 राजिन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली-110 008.

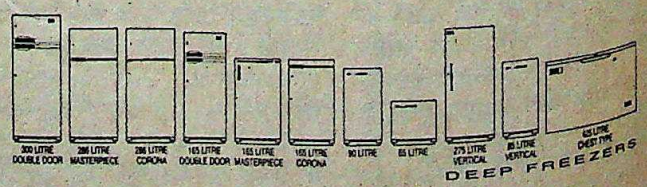

केल्विनेटर

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल अनंतप्रसाद शर्मा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राधानंदन झा, सांसद सत्येंद्रनारायण सिन्हा और उनकी पत्नी किशोरी सिन्हा भी शामिल हैं. क्रम मशहूर नेताओं में राज्य के पूर्व मंत्री उमा पांडेय, करमचंद भगत, बुद्धदेव सिंह, मिसी सदा और देवनारायण सिंह तथा विधायक आर.पी. शर्मा, आर. लाल (पूर्व पुलिस महानिदेशक) व गिरीशनारायण मिश्र हैं जिनके नाम से कॉलेज चल रहे हैं.

इनमें बहुतेरे कॉलेज तो जातीय आधार पर चलते हैं . उदाहरण के लिए राजपूत नेता और विधायक ठाकुर मुनीश्वरनाथ

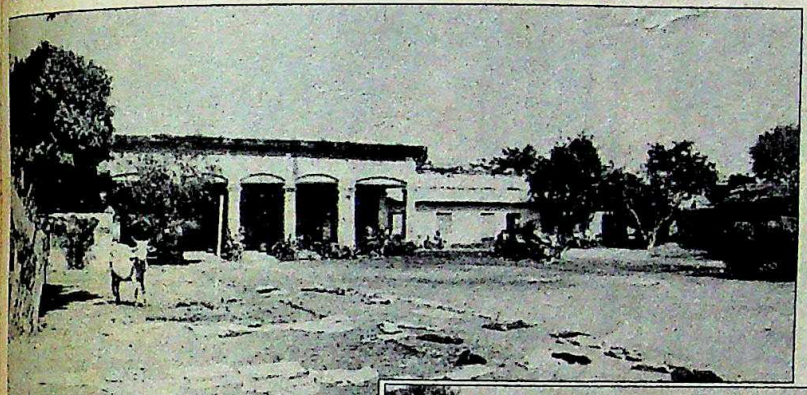

बोर्डियों के इस्तेमाल में आने वाला कॉलेज और (दाएं) वर्कशॉप के रूप में

सिंह के नाम पर कई कॉलेज हैं. इंका के सत्येंद्रनारायण सिन्हा के बाद वे अपनी जाति के दूसरे बड़े नेता हैं. इसी तरह जगन्नाथ मिश्र, कर्पूरी ठाकुर और ललितेश्वर प्रसाद शाही के नाम से चल रहे कॉलेजों का आधार भी जाति ही है.

किसी भी नेता के लिए यह धंधा खासी सहूलियत रखता है. आम तौर पर ऐसा कॉलेज खोलने के लिए तकरीबन 15 लाख की पूंजी और पांच एकड़ जमीन की जरूरत पड़ती है. शुरुआती पूंजी का ज्यादातर हिस्सा खुद अध्यापकों से ही मिल जाता है और विद्यार्थियों से ली जाने वाली फीस के कारण प्रबंधकों का फायदा दिन दूनी रफ्तार से बढ़ता रहता है क्योंकि अध्यापकों को तो नाममात्र की तनख्वाह ही दी जाती है. महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कॉलेजों की वजह से नेताओं को अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने का भी मौका मिल जाता है.

वैसे तो संबद्ध कॉलेजों में अध्यापकों की नियुक्ति कॉलेज सेवा आयोग की निगरानी में होती है पर राजनैतिक दबावों के चलते यह व्यवस्था लुंज-पुंज होकर रह गई है. ऐसी सभी नियुक्तियों में इसे सिर्फ सहमति की मुहर ही लगानी होती है.

अंगीभूत कॉलेजों के संदर्भ में ऐसी ही जिम्मेदारी रखने वाले विश्वविद्यालय सेवा आयोग की भी हालत कुछ ऐसी ही है. बिहार में सरकारी कॉलेज सिर्फ पांच हैं जबकि अंगीभूत कॉलेजों की संख्या 335 तक पहुंच गई है. इसी से जाहिर हो जाता है कि इस पूरे मामले पर राज्य सरकार का कितना नियंत्रण है.

मानव संसाधन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव आर.एस. माथुर मानते हैं कि संबद्ध कॉलेज का दर्जा देने का एक खास मापदंड है पर इसमें असल भूमिका राजनैतिक दबाव ही निभाता है. उनके हिसाब से इसकी वजह यह है कि उच्च शिक्षा के बारे में सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है और न ही राज्य की जरूरतों का कोई उपयुक्त आकलन किया गया है.

शिक्षा के धंधे से पैसा कमाने वालों का तर्क है कि वे यह सब जनता की भलाई के लिए कर रहे हैं. कुछ लोग दूसरे मकसद भी रखते हैं. जैसे—डिग्री कॉलेजों से लेकर कानून और तकनीकी के कई संस्थानों के सर्वेसर्वा, निर्दलीय विधायक आर.पी. शर्मा चाहते हैं कि उनका नाम हमेशा बना रहे. वे कहते हैं, "जब तक ये कॉलेज रहेंगे, लोग मुझे याद रखेंगे." शर्मा चंदा उगाहने और अध्यापकों के शोषण से कमाई की बात का जोरदार खंडन करते हैं, हालांकि वे खुद मानते हैं कि अध्यापकों को हर माह सिर्फ 450 रुपए वेतन ही दिया जाता है.

बाकी कॉलेज अपने मालिक का नाम बनाए रखने से ज्यादा तात्कालिक कारणों को तरजीह देते हैं. महासंघ के एक सर्वेक्षण के मुताबिक संबद्ध कॉलेजों ने 1,470 एकड़ जमीन घेर रखी है जिसकी कीमत 2.50 करोड़ है. इन पर खड़ी इमारतों की कीमत तकरीबन सात करोड़ रुपए है और फर्नीचर व प्रयोगशाला वगैरह का मूल्य करीब तीन करोड़ रुपए आंका जाता है. इन कॉलेजों के कर्त्ताधर्त्ताओं की जेबों में कितनी रकम पहुंची यह कोई नहीं जानता.

महासंघ के अध्यक्ष शर्मा ने शिक्षा के तीन बड़े धंधेबाजों—रामलखन सिंह यादव, राम अवतार वात्स्यायन और आर.पी. शर्मा की संपत्ति की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है. वात्स्यायन ने तो महिला कॉलेजों और दूसरे संस्थानों का जाल-सा बिछा दिया है. महंत विद्यानंद ने पांच संस्थान खोल रखे हैं. उनके खिलाफ कत्ल तक का आरोप है. इस सिलसिले में वे गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं और पटना में उनका जुलूस भी निकाला जा चुका है.

सरकारी दखल से बचने के लिए इन धंधेबाजों ने बहुत से तरीके ईजाद कर रखे हैं. उदाहरण के लिए राम अवतार वात्स्यायन कुछ साल पहले बौद्ध बन गए. इसलिए अब उनके सारे कॉलेज अल्पसंख्यक संस्थान हैं जिनसे ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की जा सकती.

पश्चिम चंपारण के बेतिया में महंत रामरूप गोस्वामी अपने नाम पर इसी तरह का एक कॉलेज चलाते हैं. वे अपने को कबीरपंथी कहते हैं. स्थानीय प्रशासन ने जब कॉलेज के लिए तदर्थ प्रबंधन समिति बनानी चाही तो वे अल्पसंख्यक होने की दुहाई देकर हाईकोर्ट पहुंच गए.

भारतीय जनता पार्टी के सांसद कैलाशपति मिश्र ने पिछले साल बिहार के निजी कॉलेजों का मुद्दा राज्यसभा में उठाया था. केंद्र ने राज्य सरकार से इस सिलसिले में रिपोर्ट भी मांगी थी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. अगले कुछ महीनों में पता चल जाएगा कि आजाद और झा हालात सुधारने के लिए गंभीर हैं या उस असरदार लॉबी के साथ हैं जो स्थिति को जस का तस बनाए रखना चाहती है.

—फरजंद अहमद

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'इंतजार'

आत्मतुष्ट लोगों की कथा

सईद मिर्ज़ा ने नए सीरियल के लिए अटगांव में डेरा डाला

बंबई-नासिक मार्ग के बाईं ओर एक खामोश-सा गांव है— अटगांव. यहां से गुजरने वालों का ध्यान इस ओर तभी जाता है जब क्षितिज में फैले ऊंचे पहाड़ और दाईं ओर फैली बंजर जमीन उन्हें एक कप चाय के लिए वहां रुकने को मजबूर करती है.

यदि यहां के लोगों की शक्लें जानी-पहचानी लगती हैं तो इसकी वजह यह है कि ये लोग टीवी सीरियल 'नुक्कड़' से अपनी पहचान बना चुके हैं. और अब एक बार फिर सईद और अजीज मिर्ज़ा के नए सीरियल 'इंतज़ार' में दिखाई देंगे. 26 प्रकरणों वाला यह सीरियल 11 मार्च से प्रसारित किया जाएगा.

पहले, पात्रों का परिचय—चाय की दुकान के मालिक हैं लुंगी-कुर्ताधारी सुरेश चटवाल. हमेशा अपनी मूंछों पर ताव देते रहने वाले तांगेवान बने हैं दिलीप धवन. बातूनी डाकिए की भूमिका में जावेद खां हैं जिन्हें डाक बांटने के बजाय चाय की चुस्कियों के बीच गप्पें लड़ाने में ज्यादा मजा आता है. अजय वाधवकर लाइनमैन बने हैं जो खूबसूरत जमादारिन संगीता नाईक पर लाइन मारते रहते हैं. और इन तमाम पात्रों को एक सूत्र में पिरोने वाले निर्देशक हैं अजीज मिर्ज़ा.

नाम के अनुरूप ही कहानी के सभी पात्र इंतज़ार करते नजर आते हैं— मां को बेटे की वापसी का इंतज़ार है, तांगेवाले को पैसे जोड़कर ऑटोरिक्शा खरीदने का इंतज़ार है, लद्दाख से लौटे युवक को फिर पहाड़ों में लौटने का इंतज़ार है, सहायक स्टेशन मास्टर को प्यार 'हो जाने' का इंतज़ार है.

'इंतज़ार' की कहानी उत्तर भारत के एक काल्पनिक गांव कमालपुरा की है. जब 'इंतज़ार' बनाने का विचार मन में आया तो अजीज को अटगांव की याद आई. और इस तरह इस सीरियल का जन्म हुआ. सईद और उनकी कंपनी इस्करा फिल्म्स ने 1987 के आरंभ में एक पाइलट प्रकरण की शूटिंग की और दिनेश सूटिंग और पांन पराग कंपनियों को इसे प्रायोजित करने के लिए तैयार कर लिया. अक्तूबर 1987 में कंपनी ने अटगांव में डेरा डाल दिया.

'इंतज़ार' की कहानी शुरू होती है एक वरिष्ठ, ईमानदार स्टेशन मास्टर (राजेंद्र गुप्ता) से जो बंबई से बाहर एक छोटे-से कस्बे में अपना तबादला करवाने को इच्छुक है. उसकी बेटी नेहा (सुषमा प्रकाश) प्यार में धोखा खाए बैठी है और इस निराशा में वह आत्महत्या की कोशिश भी कर चुकी है. उसके पिता का ख्याल है कि इस महानगर से बाहर जाकर ही उसकी बेटी की हालत में कुछ सुधार हो पाएगा.

नामम भोजानी

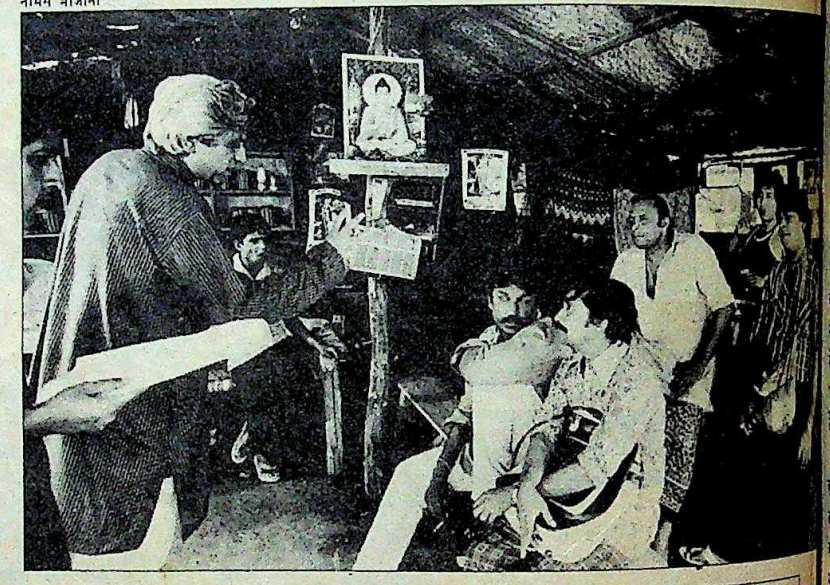

'इंतजार' एक काल्पनिक गांव कमालपुरा की कहानी है. यहां का ढाबा जनजीवन का केंद्र है जहां विचारों का आदान-प्रदान होता है और सपने सच किए जाते हैं

गांववालों की दुनिया छोटी-सी ही है लेकिन वे उसमें पूरी तरह रमे हुए हैं. एक कुली है जो अनाज के बोरे चुराकर पचास-पचास रुपए में एक बनिए को बेच देता है. एक लद्दाखी युवक सोनम (फंसोख लद्दाखी) है, जिसे परिस्थितिवश अपना घर छोड़ देना पड़ा है. एक स्कूल मास्टर (कुमुद त्रिपाठी) है, जो गांव के कुछ बच्चों को पढ़ाना ज्यादा पसंद करता है. हालांकि वह शहर में इससे कई गुना ज्यादा बच्चों को पढ़ा सकता है. एक सहायक स्टेशन मास्टर (पवन मल्होत्रा) है जिसे हर पल यही चिंता सताती रहती है कि उसकी नौकरी ठीक-ठाक चल रही है या नहीं, और अंततः वह नेहा से प्यार करने लग जाता है.

ढाबा उस गांव के जनजीवन का केंद्र है. वहां विचारों का आदान-प्रदान किया जाता है, जीवन-दर्शन जन्म लेता है, सपने सच किए जाते हैं. दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन है जो गांव को बाहर की दुनिया से जोड़ता है. बाहर की दुनिया यानी रेल के यात्री, अखबार और लॉटरी के टिकट आदि.

दर्शकों को इसमें 'नुक्कड़' की झलक मिलेगी. संगीता नाईक कहती हैं, "हां, हम कमोबेश वही रोल कर रहे हैं लेकिन हमें यह सब करना अच्छा लगता है. और इसीलिए हम मिर्ज़ा बंधुओं के साथ काम करते आ रहे हैं." 'नुक्कड़' की तरह 'इंतजार' के पात्र हमेशा पराजित नहीं होते.

सभी समान हैं, यह विचार है तो बहुत सीधा-सरल लेकिन जरूरत इसी बात की है कि इसे भुलाया न जाए. कमालपुरा की दुनिया मिर्ज़ा बंधुओं की कल्पना की दुनिया है. उनके 'नुक्कड़' के पात्र छोटे परदे पर भले ही हर बार सफल होते न दिखते हों, उनकी लोकप्रियता को देखकर तो यही लगता है कि वास्तविक जीवन में ये लोग कभी भी असफल नहीं रहें.

—सलिल त्रिपाठी, अटगांव से

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विभा मिश्रा

कशिश भरा नया किरदार

कारंत कांड और हादसे के बाद धमाकेदार वापसी

कहते हैं आग में जलकर कुंदन और निखर जाता है. कारंत कांड की नायिका विभा मिश्रा के साथ भी जैसे ऐसा ही कुछ हुआ है. भोपाल के जगप्रसिद्ध भारत भवन के रंगमंडल की अभिनेत्री विभा मिश्रा की रंगमंच पर वापसी जितनी धमाकेदार हुई है उतनी तो रंगमंच जीवन की उनकी शुरुआत भी नहीं हुई थी.

पिछले हफ्ते जब उन्होंने पु.ल. देशपांडे के मराठी नाटक 'थरा प्रकट कृपाला' के हिंदी रूपांतर 'भये प्रकट कृपाला' में अभिनेत्री की भूमिका अदा की तो हॉल खचाखच भरा हुआ था. और यह कोई अकेला उदाहरण नहीं है. पिछले वर्ष सितंबर में जब से उन्होंने रंगमंच पर दोबारा कदम रखे तब से अब तक वे 14 नाटकों में अभिनय कर चुकी हैं और हर शो बेहद कामयाब रहा है.

लगभग दो साल पहले चेहरे को छोड़कर उनका लगभग पूरा बदन (71 प्रतिशत हिस्सा) जल गया था. अस्पताल के बिस्तर पर मौत और जिंदगी के बीच झूलते हुए उन्होंने छह माह गुजारे. यह सुंदर 28 वर्षीय अभिनेत्री मनुष्य की जीजिविषा, अदम्य साहस और इच्छा शक्ति का ही बेहतरीन उदाहरण है कि वे फिर से जलती दुनिया में लौट आई हैं. पिछले साल वे जर्मन निर्देशक रिट्ज़ बेनेविट्ज़ के 'तो सम पुरुष न मो सम नारी' (शेक्सपियर के 'टेमिंग ऑफ द श्रू' का बुंदेली रूपांतर) की हीरोइन के रूप में भारत भवन के स्टेज पर उतरी थीं. मिश्रा कहती हैं, "अस्पताल में भी मुझे लगता था कि अगर थियेटर नहीं कर पाए तो जीने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा."

तेईस मई 1986 की उस मनहूस दोपहर को, और उसके बाद की घटनाओं को, विभा मिश्रा एक 'घटिया स्क्रिप्ट' के रूप में खारिज करती हैं. उस दिन वे अपने घर में बुरी तरह जल गई थीं. पुलिस ने बाद में उनके पति और रंगमंडल के 58 वर्षीय डायरेक्टर ब.वा. कारंत को, जो वारदात के समय मौजूद थे, विभा को जलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद एक 'सेक्स स्कैंडल' और अवैध प्रेम-गाथा के रूप में (कारंत शादीशुदा हैं और मिश्रा अविवाहित) चटखारे लेकर उछाली गई यह घटना हफ्तों सुर्खियों में छाई रही.

जिस तरह के स्कैंडल में मिश्रा घिरी थीं, उसका कामयाबी के साथ मुकाबला करना और उससे उबर पाना भी विरलों के ही वश में होता है. पर वे ठीक होते ही पूरे आत्मविश्वास के साथ न केवल भोपाल

प्रकाश हतवालने

'...न मो सम नारी' में विभा की मुद्रा

वापस आईं, बल्कि लगभग दंभ की मुद्रा में उसी मकान में फिर रहने गईं जो पुलिस की डायरी में 'मौका-ए-वारदात' था और आस-पड़ोस वालों की नजर में आकर्षण केंद्र.

"मुझे लगा," उन्होंने इंडिया टुडे को बताया, "स्थितियों को सामान्य करने का इससे बेहतर तरीका हो ही नहीं सकता था. फिर मैंने यह भी सोचा कि ऐसी क्या गलती की है मैंने जो शहर छोड़ना पड़े."

थियेटर मिश्रा की जिंदगी है. "मैं केवल जिंदा रहना नहीं चाहती थी." उन्होंने अस्पताल के दिनों को याद किया. बीमारी में सारे बाल झड़ गए थे. छह महीने बाद पहली दफा शीशा देखा तो बहुत रोई. बोलीं, "एक्टर को तो अपने नाखून से भी मोह होता है." अपने बदन पर जलने के भद्दे निशानों को देखकर उन्हें कभी-कभी अपने-आप पर भी शक होता था—कोई बड़ा रोल वे निभा पाएंगी या नहीं. पर यह सारी शंका तब दूर हो गई जब बेनेविट्ज़ ने उन्हें 'तो सम पुरुष न मो सम नारी' में प्रमुख भूमिका के लिए चुना. तब से उन्होंने मुड़कर नहीं देखा है.

लखनऊ के एक निम्न मध्यमवर्गीय परिवार में जन्मी—"घरवाले नहीं चाहते थे कि मैं थियेटर का कैरियर चुनूं"—विभा मिश्रा ने रंग जीवन की शुरुआत वहां के भारतेंदु नाट्य केंद्र से की. '79 से '82 तक वह राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एनएसडी) में पढ़ी और फिर उसी साल भोपाल के नए-नए खुले रंगमंडल में गई— एनएसडी के अपने गुरु कारंत के सान्निध्य में.

उस जमाने में रंगमंच के बाहर किसी ने उनका नाम भी नहीं सुना था. प्रसिद्धि तो उन्हें कारंत कांड के बाद ही मिली. "प्रसिद्धि नहीं कुख्याति," वे हंसकर सुधारती हैं. जाहिर है, ऐसी प्रसिद्धि चिढ़ ही उपजाएगी. वे बड़ी गंभीरता से अपना नाम बदलने की सोच रही हैं. वे बोलीं, "समाज अगर विभा मिश्रा को यह चरित्र दे रहा है तो मैंने उसे छोड़ दिया. हमारी तो आदत ही है कि आज एक रोल तो कल दूसरा."

कारंत और मिश्रा दोनों अपनी जिंदगी को नए सिरे से जमाने की कोशिश कर रहे हैं. कारंत इन दिनों केवल मुकदमे की पेशी के लिए भोपाल आते हैं. उनका ज्यादातर वक्त फिल्मों और टीवी के लिए काम करने में ही बीतता है ताकि "अपने ऊपर चढ़ गए कर्जों को पटा सकूं." और मिश्रा उन तथ्यों से रू-ब-रू होने की कोशिश कर रही हैं जिन्हें केवल किरदारों में ही उन्होंने जीया था. पर उनकी जिंदगी के ताने-बाने उस मुकदमे से भी जुड़े हैं, जिसका फैसला बहुत जल्द संभव है. भोपाल की अदालत उनकी जिंदगी का भी फैसला करेगी.

—नरेंद्र कुमार सिंह

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बैडमिंटन

विजय में पराजय की आहट

थॉमस कप में सिक्का तो जमाया पर भविष्य अनिश्चित

यह एक ऐसी जीत थी जिससे भविष्य में पराजयों का संकेत मिलता है. पिछले महीने जब नई दिल्ली में भारत ने थाइलैंड को पराजित करके बैडमिंटन के थॉमस कप मुकाबलों के अंतिम दौर में जगह बनाई, उस समय जिस तरह की नाउम्मीदी भरी खुशी मनाई गई कम-से-कम उससे तो ऐसा ही आभास होता है.

मई में कुआलालंपुर में विश्व चैंपियन होने का गौरव पाने के लिए जो आठ टीमें भिड़ेंगी, उनमें भारत को जगह पाने के बावजूद बहुत उम्मीदें नहीं बंधतीं. ऐसा नई दिल्ली में मिली जीत से ही स्पष्ट है क्योंकि यह जीत इस दमखम वाले खेल के हिसाब से बुढ़ाते, 33 वर्षीय प्रकाश पादुकोण ने दिलाई.

पादुकोण के बाद अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में भारत का क्या होगा, यह सवाल सबको परेशान कर रहा है. महिला खिलाड़ियों के मामले में तो संभावनाएं पहले से ही धुंधली हैं. राष्ट्रीय चैंपियन मधुमिता बिष्ट की मौजूदगी के बावजूद जापान ने भारत को 5-0 से हराकर उबेर कप मुकाबलों से उसे बाहर कर दिया.

लेकिन कुआलालंपुर में क्या होगा? अभी का सारा अनुमान भारत के पक्ष में नहीं लगता. 1940 के दशक में राष्ट्रीय टीम में रहे एस.एल. जैनी कहते हैं, "अगर हम छठे स्थान पर भी आ गए तब भी गनीमत होगी." पादुकोण भी मानते हैं, "अगर हमने एक या दो जीतें भी हासिल कर लीं तो बहुत होगा."

भारतीय बैडमिंटन संघ नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने ही नहीं, राष्ट्रीय खिलाड़ियों की जरूरतों को पूरा करने में भी असफल साबित हुआ है. पैसे की समस्या लगातार बनी हुई है. जैसे मधुमिता 20 दिन चलने वाली यूरोपीय सर्किट प्रतियोगिता में भाग तो लेंगी पर इसके लिए उन्हें अपनी जेब से करीब 15 हजार रुपए खर्च करने पड़ेंगे. मधुमिता कहती हैं, "हां, अब तो हम इन बातों के आदी हो गए हैं."

बुनियादी सुविधाएं भी बड़ी मुश्किल से मिलती हैं. राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में घटिया देसी शटल की जगह आयातित शटल इस्तेमाल हो इसके लिए पादुकोण को बॉयकाट की धमकी तक देनी पड़ी. हाल में दिल्ली में हुए मैचों के दौरान भी यमुना वेलोड्रोम में, जहां खिलाड़ी ठहरे हुए थे, व्यायाम के उपकरण उपलब्ध नहीं थे.

प्रतिद्वंद्विता का स्तर बढ़ते जाने के साथ ही खिलाड़ियों का फिटनेस का स्तर बढ़ाने के लिए दुनिया भर में नई तकनीकें अपनाई जाने लगी हैं पर भारत में अभी तक इस दिशा में कुछ भी नहीं हुआ है. राष्ट्रीय चयनकर्ता दमयंती तांबे, जो राष्ट्रीय चैंपियन रह चुकी हैं, बताती हैं कि इंडोनेशिया जैसे देशों में साल में छह महीने तक फ़िटनेस कैंप चलते हैं जबकि भारत में ऐसे शिविर बमुश्किल दो महीने ही चलते होंगे.

जहां तक खेल की रणनीति का सवाल है, डबल्स के विशेषज्ञ खिलाड़ी तैयार हों यह बात भारत में जड़ें ही जमा नहीं पा रही है. पादुकोण कहते हैं, "चीन और इंडोनेशिया जैसी टीमों को हराने के लिए हमारे पास सिंगल्स के अलावा डबल्स खेलने वाले अच्छी जोड़ियां भी होनी चाहिए."

भविष्य के लिए स्पष्ट नीति रहनी चाहिए, इस बात की जरूरत को बैडमिंटन संघ ने हाल में महसूस करना शुरू किया है. आजकल जूनियर खिलाड़ियों की टीम हालैंड वगैरह देशों में खेलने गई है. लेकिन सचाई यह भी है कि चयनकर्ताओं ने हरएक अपनी गद्दी सुरक्षित रखने के ख्याल से नए खिलाड़ियों को मौका ही नहीं दिया. जैसे भारत जब नेपाल और श्रीलंका जैसी हल्की टीमों से खेल रहा था तब भी हरजीत जैसे नए खिलाड़ियों को मौका नहीं मिला. यूरोपीय सर्किट खेलने वाले भारतीय रन का सबसे नौजवान खिलाड़ी 'मात्र' 24 का है. इससे पता चलता है कि देश में नई प्रतिभाओं को कैसा 'प्रोत्साहन' मिल रहा है.

अगर बैडमिंटन संघ भविष्य के बारे में ठोस योजनाओं पर अमल नहीं करता तो अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य से भारत का सितारा अस्त होने में बहुत देर नहीं है. दमकर कहती हैं, "भारत में बैडमिंटन की बढ़ावा दिया जाए इस बारे में काफी अनुसंधान की जरूरत है. कहीं-न-कहीं कमी जरूर है." अगर वे यह कहतीं कि जगह काफी कुछ कमी है, तो यह सचाई ज्यादा करीब होता.

पाना

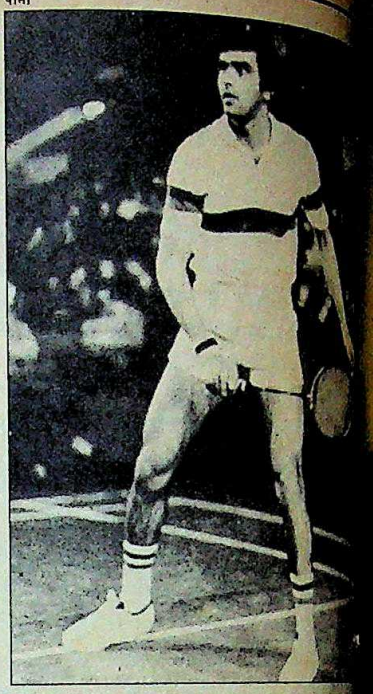

पादुकोण: उत्तराधिकार का संकट

मधुमिता: बात बनती नहीं

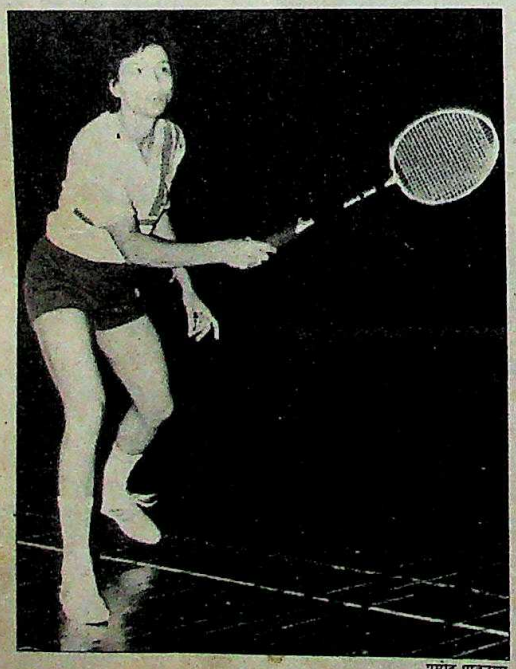

प्रमोद पुष्करणा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

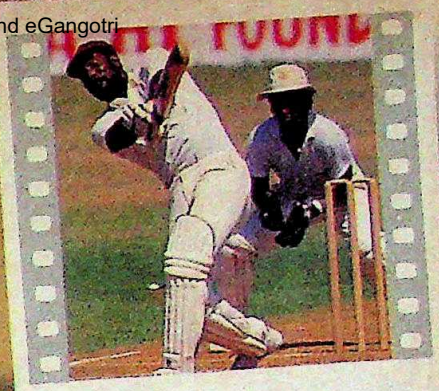

धुंआधार बल्लेबाज़ का शानदार रुआब

विवियन रिचर्ड्स. धुंआधार बल्लेबाज़, रंग भेद नीति के विरूद्ध आवाज़ उठाने वाले, रेगे संगीत के शौकीन, शानदार व्यक्तित्व के मालिक.

और यहाँ विव के व्यक्तित्व का एक और रूप-विमल सूटिंग में. मोतिया सफ़ेद जोधपुरी-मेन्डेरिन कॉलर-बंद गले वाला. चौड़े पुष्ट कंधे, सामने ५ बटन साइड वेंट और फ्लैप पॉकेट वाले इस सूट ने केरेबियन खिलाड़ी विव रिचर्ड्स का दिल जीत लिया है.

VIMAL®
A RELIANCE PRODUCT

पॉलिसीय और
वूल ब्लेन्डिड सूटिंग्स

विजेताओं की शान!

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

युद्धकलाएं

करतबों का चढ़ता जादू

कोरियाई और जापानी युद्धकलाओं की लोकप्रियता बढ़ी

अपने दांवपेच, चीख-चिल्लाहट और हवाई कलाबाजियों के साथ युद्धकलाएं आखिरकार भारत पहुंच ही गई हैं. हाल में दो नई बातों से इन कलाओं को गति मिली है, उनमें एक नया उत्साह जागा है. पिछले एक साल में कोरियाई युद्धकला 'ताइ क्वोन दू' पूरे उत्तर भारत में छा गई है. इसमें कराते के मुकाबले किक पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है. पर कराते भी पीछे नहीं रहा. पिछले महीने बंगलूर में शिबूकन शोरिजीर्यु केनकीकन स्कूल खुलने के साथ ही यह देश कोशकी या प्रतियोगात्मक कराते के युग में प्रवेश कर गया.

युद्धकला के परंपरागत प्रशिक्षण में कभी भी चोट नहीं पहुंचाई जाती पर कोशकी के दांवपेच किसी का भी काम तमाम कर सकते हैं. इस कारण कराते को युद्धकलाओं की लोकप्रियता पाने की होड़ में आगे निकलने में आसानी हो सकती है. वैसे कराते की गोजू, वदोई चिटो, शोतोकन, शोरिन वगैरह शैलियां पहले से ही लोकप्रियता पाने के लिए मैदान में डटी हुई हैं.

कोशकी के प्रणेता 48 वर्षीय मासायुकी हिसाताका शिबूकन स्कूल के उद्घाटन के सिलसिले में भारत आए थे. हिसाताका को नौ डिग्री का ब्लैक बेल्ट खिताब मिला हुआ है. वे जापान के शोरिंजीर्यु स्कूल के प्रधान हैं. बंगलूर का स्कूल इसी से संबद्ध है. उन्होंने बताया कि कोशकी में असल में वार 40 फीसदी क्षमता से ही किया जाता है.

हिसाताका ने एक दशक पहले जब यह शैली ईजाद की थी तो प्राणघातक वारों से बचने के लिए खास किस्म का सुरक्षा कवच भी तैयार किया था. समुराई लड़ाकों के कवच-बख्तर से प्रेरणा लेकर उन्होंने हल्के बुलेटप्रूफ कांच से एक हेल्मेट और एक छाती कवच तैयार किया. 4,000 रुपए का यह सेट अब भारत में भी मिल सकेगा. अब हर तकनीक को परखना आसान हो जाएगा. "इन चीजों पर पड़े हर मुक्के, हर वार की आवाज व असर से अंक गिने जा सकते हैं." उन्हें उम्मीद है कि इससे कराते प्रतियोगिताओं को ओलंपिक का दर्जा मिल सकता है.

वेंकटेश एल्लोरे

वेंकटेश एल्लोरे

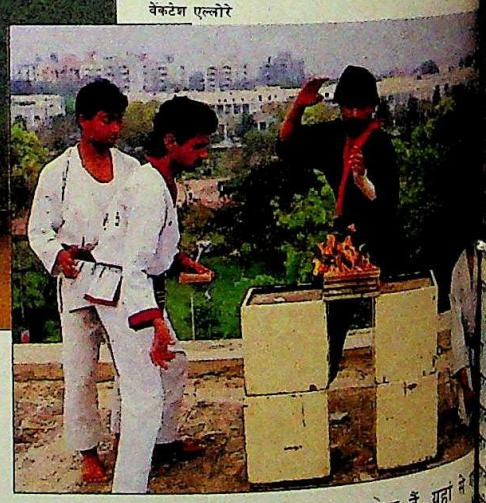

कराते का वार और कवच का प्रयोग (ऊपर); कराते कलाकार का करतब

ओलंपिक मुकाबलों की संभावना ही असल में इन दिनों युद्धकला के कलाकारों का हौसला बढ़ा रही है. जूडो तो पहले से ही एक ओलंपिक खेल है. पर इस दौड़ में सबसे आगे है 'ताइ क्वोन दू'. यह 1986 में सिओल एशियाड में शामिल किया गया था. अब इसने सिओल ओलंपिक में प्रदर्शन खेल के तौर पर शामिल होने की जगह बना ली है. कराते के तरफदार कहते हैं कि यह एक अस्थायी उपलब्धि है, क्योंकि ओलंपिक कोरिया में हो रहे हैं. लेकिन कराते के लिए भी रास्ता सुगम नहीं दिखता. इसकी सबसे बड़ी समस्या है शैलियों की इसकी विविधता. [illegible] किसी भी शैली के लोग किसी दूसरी [illegible] के मानदंडों को आसानी से नहीं मानते. [illegible] वजह से, कम-से-कम फिलहाल तो [illegible] क्वोन दू' आगे निकल गया है. भारत में [illegible] भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन [illegible] की मान्यता मिल गई है. इसके गुरुओं में काफी उत्साह है. 1980 [illegible] भारतीय 'ताइ क्वोन [illegible] फेडरेशन की स्थापना करने वाले 35 वर्षीय [illegible] जिमी. जगतियानी कहते हैं, "मेरा मकसद इस [illegible] को आज क्रिकेट जितना लोकप्रिय बनाना है. और मुझे पूरा विश्वास है कि यह हो जाएगा." उनका दावा है कि 25 राज्यों में 27,000 लोग उनके संगठन के सदस्य हैं.

कराते के मुकाबले 'ताइ क्वोन दू' में पैरों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है. इसमें शैली पर जोर कम होता है और ताकत के बजाय गति पर ज्यादा जोर दिया जाता है. सिर्फ बंबई में ही इसके 18 स्कूल हैं जिनमें हरेक में औसतन 50 छात्र हैं. यहां से महाराष्ट्र के 20 जिलों में फैल गया. दिल्ली में हाल ही में कोरियाई कला के [illegible] दर्जन स्कूल खुल गए हैं. इनमें से पांच [illegible] में पढ़ाने वाले 26 वर्षीय अभय सिंह [illegible] हैं, "छात्रों में काफी उत्साह है."

हालांकि 'ताइ क्वोन दू' में कराते की [illegible] परस्पर विरोधी शैलियों वाली दिक्कत [illegible] है. लेकिन इसमें भी विभिन्न धाराएं [illegible] अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसके दो महासंघ [illegible] एक, उत्तर कोरिया से संचालित होता है [illegible] दूसरा दक्षिण कोरिया से. भारत में [illegible]

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

के लिए अभिशाप बन गया है. प्रशिक्षक बहुत सस्ते हो गए हैं. उनके पास कई तरह की शैलियां हैं, कई तरह के महासंघ. इन पर नियंत्रण नाममात्र का ही है. हिंदुस्तान में लोग बिना किसी हैसियत के ही ब्लैक बेल्ट हासिल कर लेते हैं और स्कूल खोल देते हैं.

राजधानी के मॉडर्न स्कूल की वसंत विहार शाखा में कराते सिखाने वाले 28 वर्षीय राजिंदर 'हैप्पी' ग्रोवर कहते हैं, "यह अब धंधा बन गया है. आपकी

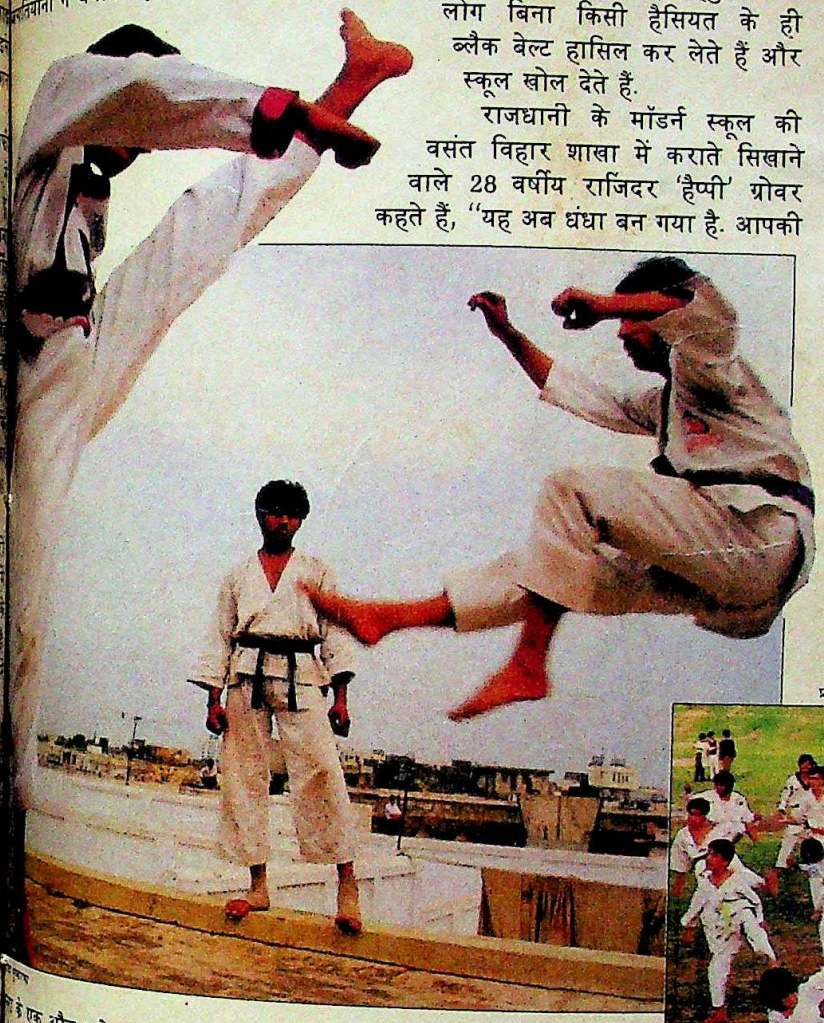

प्रमोद पुष्करणा

'ताइ क्वोन डू' शैली की किक (ऊपर); और स्कूली बच्चों का प्रशिक्षण

जेब में पैसा है तो आपको बेल्ट मिल जाएगी." वे बताते हैं कि कोई भी प्रशिक्षक अपने छात्र को निराश करके उसे खोना नहीं चाहता. साथ ही परीक्षा की फीस 1,200 रुपए है, जो बहुत ज्यादा है. पर आमदनी बुरी नहीं है. महीना अच्छा गुजरा तो कुछ प्रशिक्षक 10,000 रुपए तक कमा लेते हैं. जाहिर है, इसका ज्यादातर हिस्सा अमीर छात्रों से मिलता है.

जगतियानी बताते हैं कि युद्धकलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार कुछ नहीं करती. प्रशिक्षक अपनी कक्षाएं पार्कों, स्थानीय क्लबों और यहां तक कि अपने घर के पिछवाड़े में लगाते हैं. उनके मुताबिक, "अगर हमें युवकों को प्रशिक्षण देने की सही सुविधाएं मिलें तो भारत में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है."

इन कक्षाओं में ज्यादातर लोग आत्मरक्षा के गुर सीखने के लिए ही आते हैं, लेकिन जो खुद स्कूल खोलना चाहते हैं उनकी दिलचस्पी प्रतियोगिताओं में होती है. लेकिन सभी लोग इस बात पर एकमत दिखते हैं कि युद्धकलाओं का प्रशिक्षण उन्हें गुस्सैल नहीं बनाता. ब्लैक बेल्ट प्राप्त खूबसूरत 25 वर्षीया वाणी शर्मा के मुताबिक, "अब हर कोई मुझे कहता है कि कराते सीखने के बाद तुम्हारा गरम मिजाज ठंडा हो गया है."

अविनाश सुब्रमण्यम (27) कहते हैं, "आप इस तकनीक को जितना ज्यादा सीखते हैं उतना ही इस कला से अनभिज्ञ आदमी से भिड़ने की इच्छा कम हो जाती है. स्कूल में मैं काफी कमजोर था और डरा-डरा रहता था. पर एक बार जब मैंने कराते सीख लिया तो मैं बिलकुल बदल गया. मैंने पाया कि पहले जिन गंदी फब्तियों से मैं बहुत भड़क उठता था, उन पर अब ध्यान भी नहीं देता." सुब्रमण्यम अब न्यू शोरिंजीर्यू स्कूल में मुख्य प्रशिक्षक हैं. वे नौजवानों को युद्धकलाएं सिखाने के महत्व पर बहुत जोर देते हैं. वे मानते हैं, "किशोर अक्सर नशीली दवाओं और शराब से अपनी शक्ति बरबाद करते हैं. युद्धकलाओं से यह सारी ऊर्जा इस्तेमाल की जा सकती है. एक बार अगर शरीर भरा-पूरा और कारगर बन गया तो हर कोई परवाह करेगा कि यह सिगरेट या शराब से बरबाद न हो." जाहिर है कि विभिन्न युद्धकलाओं के लिए बढ़ता उत्साह हर तरह से अच्छा है. खुदा इसके दांवपेचों को और ज्यादा ताकत बख्शे.

—डेविड देवदास और अनीता प्रताप
ब्यूरो रिपोर्टों के साथ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

◆ अगर विज्ञापन फिल्मों की शूटिंग से फुर्सत हुई तो वह स्नूकर प्लेटफार्म पर गेंद 'शूट' कर रही होती है. 1986 में 'मिस इंडिया' का ताज पहनने के बाद से ही 19 वर्षीया मॉडल **मेहर जेस्सिया** का इस खेल पर 'दिल आ गया था.' 1988 का खूबसूरत चेहरा मानी जाने वाली इस रूपसी ने विमल, स्टे-फ्री और फॉरहेंस समेत 15 विज्ञापन फिल्मों में काम किया है. अपने खेल में भी हाथ मारती हुई भारत सुंदरी पिछले साल इंडियन ओपन स्नूकर चैंपियनशिप के महिलाओं के सेमी-फाइनल तक जा पहुंची.

◆ माकपा के 54 वर्षीय तेजतर्रार सांसद **अमल दत्त** अगर मार्क्स की दुहाई देते हैं तो राजीव गांधी भी. लेकिन दोनों के मार्क्स एक नहीं हैं. योजना आयोग के सदस्यों को 'जोकर' कहने के मामले पर जब दत्त ने लोकसभा में राजीव से सवाल किया तो उन्होंने उलटे खुद सवाल कर दिया, "क्या ग्रूचो?" अमेरिकी हास्य कलाकार ग्रूचो मार्क्स के नाम का उद्धरण वहां मौजूद अधिकांश सांसदों के सिर के ऊपर से गुजर गया. दत्त ने कहा, "हमारे बार-बार हस्तक्षेप के कारण राजीव भन्ना गए." दत्त ने भी स्वीकार किया कि उन्हें ग्रूचो, हारपो की कामेडी के बारे में जानकारी नहीं थी. उन्होंने कहा, "बाद में मुझे मालूम हुआ कि राजीव गांधी ने हाल ही में अमेरिकी दूतावास की कुछ फिल्में देखी थीं. उनमें से एक इन मार्क्स बंधुओं की थी. अगली बार हो सकता है मैं प्रधानमंत्री को हारपो कहकर अपना हिसाब बराबर कर लूं."

जेस्सियाः पक्का निशाना

अमल दत्तः मसखरी का चक्कर

प्रभात पटियार

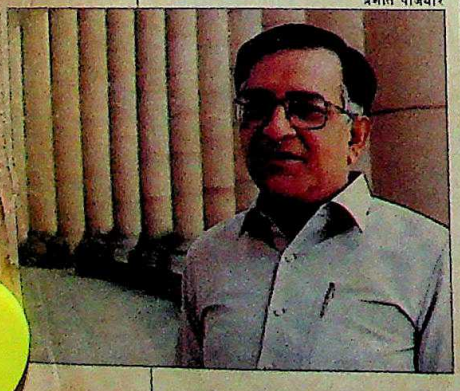

◆ खेल राज्यमंत्री **मार्गरेट अल्वा** निश्चय ही अपने मंत्रालय का काम अपने व्यवहार में भी उतारती हैं. होली की संध्या पर एक महिला मेले में अल्वा ने अपनी जानी-पहचानी साड़ी में दूसरी ढेरों महिलाओं के साथ एक दौड़ में हिस्सा लिया. दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में इस ओपन स्पोर्ट्स मीट में रस्साकशी के खेल में तो वे जीत गईं लेकिन 35 साल से ऊपर आयु वाली महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में वे पीछे रह गईं. खेल का भरपूर आनंद लेती हुई अल्वा ने कहा, "मुझसे अधिक उम्र वाली महिलाएं पहले ही दौड़ गईं इसलिए मैं उन्हें पकड़ नहीं पाई." अपने

अल्वाः खेल (मंत्री का) भार

को चुस्त-दुरुस्त रखने के लि वे नियमित रूप से बैडमिंटन खे हैं. उन्होंने बताया, "मेरी बेटी मुझे दौड़ाती रहती है."

◆ राष्ट्रभक्ति जैसे उद्देश्य के लिए यह एकदम नया तरीका अपनाया गया है. जनता पार्ट एच.एम. पटेल को लगता है "सरदार पटेल जैसे महान स्वतंत्र सेनानियों की उपेक्षा की जाती है इसीलिए उन्होंने 'भारत स्वतंत्रता संग्राम पर फिल्म फाउ डेशन' की स्थापना की है. पैसों के लिए 1000 रु. के करमुक्त बॉन्ड रखे गए हैं. इसकी पहली फिल्म होगी—भारत का नरेंद्र जिसके निर्देशक हैं केतन मेहता श्याम बेनेगल सहयोगी होंगे. गायक कार **विजय तेंदुलकर** भारत के इ पहले उप-प्रधानमंत्री के जीवन प पटकथा तैयार कर रहे हैं. विषय अध्ययन कर रहे तेंदुलकर ने क "पटेल एक दिग्गज थे, जिनके से अनेक विरोध थे, फिर भी दोनों ने एकजुट होकर काम किय

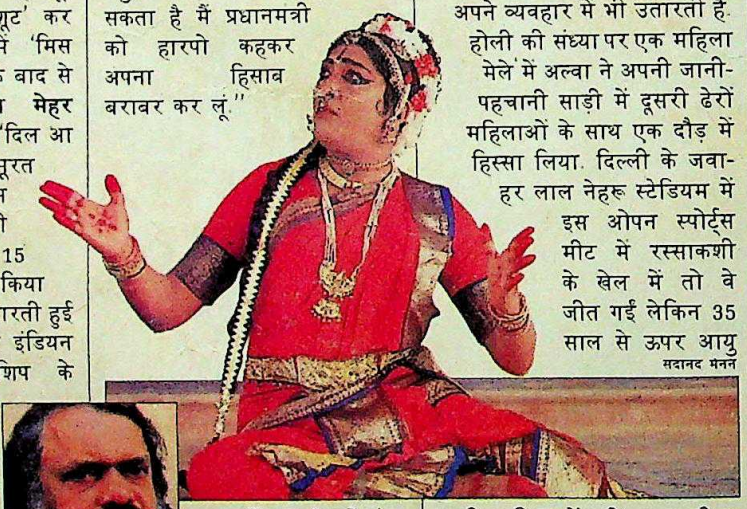

अर्रविंदन (इनसेट) और फिल्म का दृश्य

◆ **जी. अर्रविंदन** की फिल्म को न दिखाने का फैसला गैर-कूटनीतिक था. लेकिन मॉस्को में भारत के जाने-माने राजदूत टी.एन. कौल को लगा कि इसे दिखाया जाना ठीक नहीं होगा. अर्रविंदन का वृत्तचित्र 'सहज' नारी की भूमिका निभाने वाले पुरुष नर्तकों के बारे में है. गुरु केलुचरन महापात्र जैसे कलाकारों ने सोवियत रूस में चल रहे भारत उत्सव के तहत एक नारी प्रदर्शनी के अवसर पर इसमें अर्धनारीश्वर की अवधारणा को चित्रित किया था. कौल को लगा कि इसमें तो उनके देशवासियों को हिजड़ा दिखाया गया है. अरविंदन ने कहा, "हमारी सांस्कृतिक विरासत के प्रति नौकरशाही में बढ़ते अज्ञान के कारण ही यह हुआ है."

मेहता (बाएं) और तेंदुलकरः नई दिशा में एक प्रयास

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

किस्सा कुर्सी पलटने की कोशिश का

पूर्व राष्ट्रपति जैल सिंह के कार्यकाल के अंतिम दिनों में राष्ट्रपति भवन राजीव गांधी सरकार का तख्ता पलटने की साजिशी सियासी सरगर्मियों का जैसे केंद्र बन गया था. उस दौर में दिन-प्रतिदिन चलने वाली जोड़तोड़ का सिलसिलेवार ब्यौरा पहली बार.

आवरण कथा 18

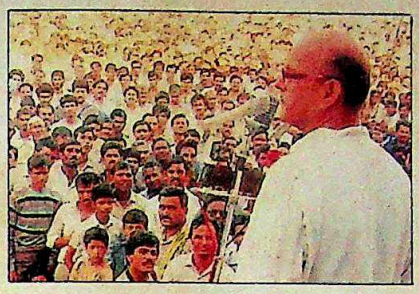

खंदक की लड़ाई का बिगुल

इलाहाबाद का संसदीय उपचुनाव सत्ताधारी दल के स्टार उम्मीदवार अमिताभ बच्चन और जनमोर्चा नेता वी.पी. सिंह के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष साबित हो सकता है. दोनों उम्मीदवारों की चुनावी रणनीति का मूल्यांकन और साथ में जनमत सर्वेक्षण के नतीजे.

खास रपट 74

दक्षिण पर तूफानी धावा

इंका महासमिति 32 वर्षों बाद पहली बार दक्षिण में अपना अधिवेशन करने जा रही है. यानी दक्षिण में विपक्ष के गढ़ को नेस्तनाबूद करने की तैयारी जारी है. हाथ से निकल गए दक्षिणी राज्यों को एक बार फिर जीतने की इंका की रणनीति का रहस्योद्घाटन.

खास रपट 62

बीते वैभव की पुनर्स्थापना

हिंदू पौराणिक कथाओं के प्रतीकों से भरपूर कंपूचिया के अंगकोर वाट मंदिर में भारतीय कदम एक बार फिर पड़े हैं. लेकिन इस बार इस तबाह मंदिर के पुनरुद्धारक के रूप में. वे इस मंदिर को उसके पुराने वैभवशाली स्वरूप में लाने का प्रयास कर रहे हैं.

विशेष लेख 48

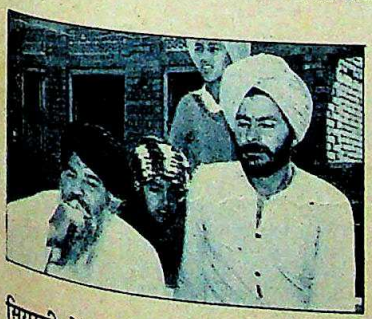

सियासी खेल के शिकार

केंद्र सरकार की नई किंतु अस्पष्ट पंजाब नीति के तहत जोधपुर जेल के 365 में से 40 बंदी हाल में रिहा किए गए. जिन हालात में वे बंदी बनाए गए उन हालात का बयान और जो रिहा नहीं किए गए उन बंदियों के भविष्य के बारे में विस्तृत रिपोर्ट.

विशेष लेख 70

अमन का लंबा दौर खत्म

डीटीसी, कोयला उद्योग, विमान सेवा, रेल सेवा—तमाम सार्वजनिक उपक्रमों के कामगारों के तेवर इन दिनों उग्र हैं. इसके पीछे वजह क्या है और इसके कारण अर्थ-व्यवस्था पर बोझ कितना है, और भावी दिशा क्या है. एक आकलन.

कारोबार 78

अगले पन्नों पर

कसौटी 13
तेवर 14
राजरंग 15
हिंदोस्तां हमारा 16
बीता पखवाड़ा 17
आवरण कथा
किस्सा राजीव की कुर्सी
पलटने की कोशिश का 18
आजकल
कांग्रेस (इ) : पुराने नेताओं का पुनर्वास ... 28
इंडियन एक्सप्रेस : नहले पर दहला 30
चड्ढा : उलझी गुत्थी में नया पेंच 31
पश्चिम बंगाल : हिंसा का जुनून 32
ठाणे : मासूम की नामालूम मौत 33
पंजाब : कथनी और करनी का फर्क 34
जबलपुर : भयानक हादसा 36
नक्सली संगठन : बदलते तेवर 37
जयपुर घराना :
महल की लड़ाई सड़क पर 38
बंबई : शेर की गुर्राहट 40
आखिरी बात 41
राज्य-दर्पण 42
विशेष लेख
अंगकोर वाट :
बीते वैभव की पुनर्स्थापना 48
पर्यावरण
राष्ट्रीय समुद्री उद्यान :
अस्तित्व का संकट 61
खास रपट
कांग्रेस (इ) : दक्षिण पर तूफानी धावा ... 62
प्रतिरक्षा
ए.बी. देवय्या : शौर्य की बिसरी गाथा 68
विशेष लेख
जोधपुर के बंदी :
सियासी खेल के शिकार 70
खास रपट
इलाहाबाद : खंदक की लड़ाई का बिगुल ... 74
व्यापार चक्र 77
कारोबार
सार्वजनिक उपक्रम :
अमन का लंबा दौर खत्म 78
टेक्नोजर्मा : सहयोग के सूत्र 80
पीथमपुर : प्रगति को पाला 81
चॉकलेट बाजार : होड़ का जायका 82
विज्ञान चर्चा 84
वन्य जीवन
बंबई : जंगल में अमंगल 85
खेलकूद
लॉन टेनिस : घाटा ही घाटा 86
अपराध
मादक दवा नियंत्रण :
कामयाबी की नई उम्मीदें 88
आंध्र प्रदेश : रक्तरंजित संघर्ष गाथा 89
धरोहर
इंदौर : विरासत का विनाश 91
रहन-सहन
टीपू सुल्तान के वंशज :
जाने कहां गए वो दिन 92
किताबें 99
चर्चित चेहरे 104

आवरण : भवान सिंह

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Handloom Emporium is much more than this...

Sarees

Readymades–Men

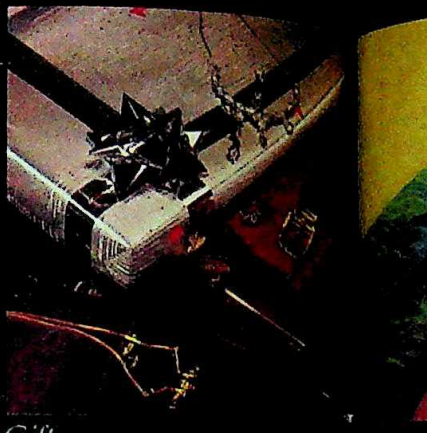

Gifts

Children's Wear

Furnishings

Silks

Tailoring

Travel Goods

Ensembles—Women

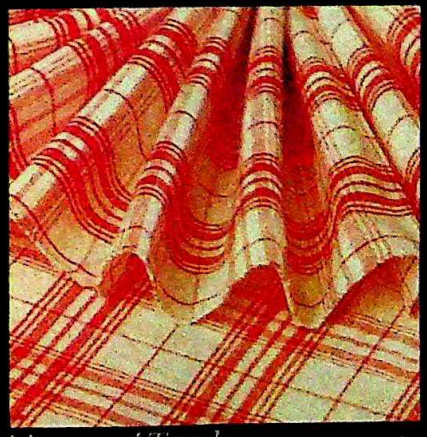

Linen and Towels

and Care...

It is Elegance. Style. And Class.

handloom® emporium

G 12 SOUTH EXTN 1 NEW DELHI 110049 PH 623

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

स्वच्छता का निखार
तरो ताज़गी की बहार

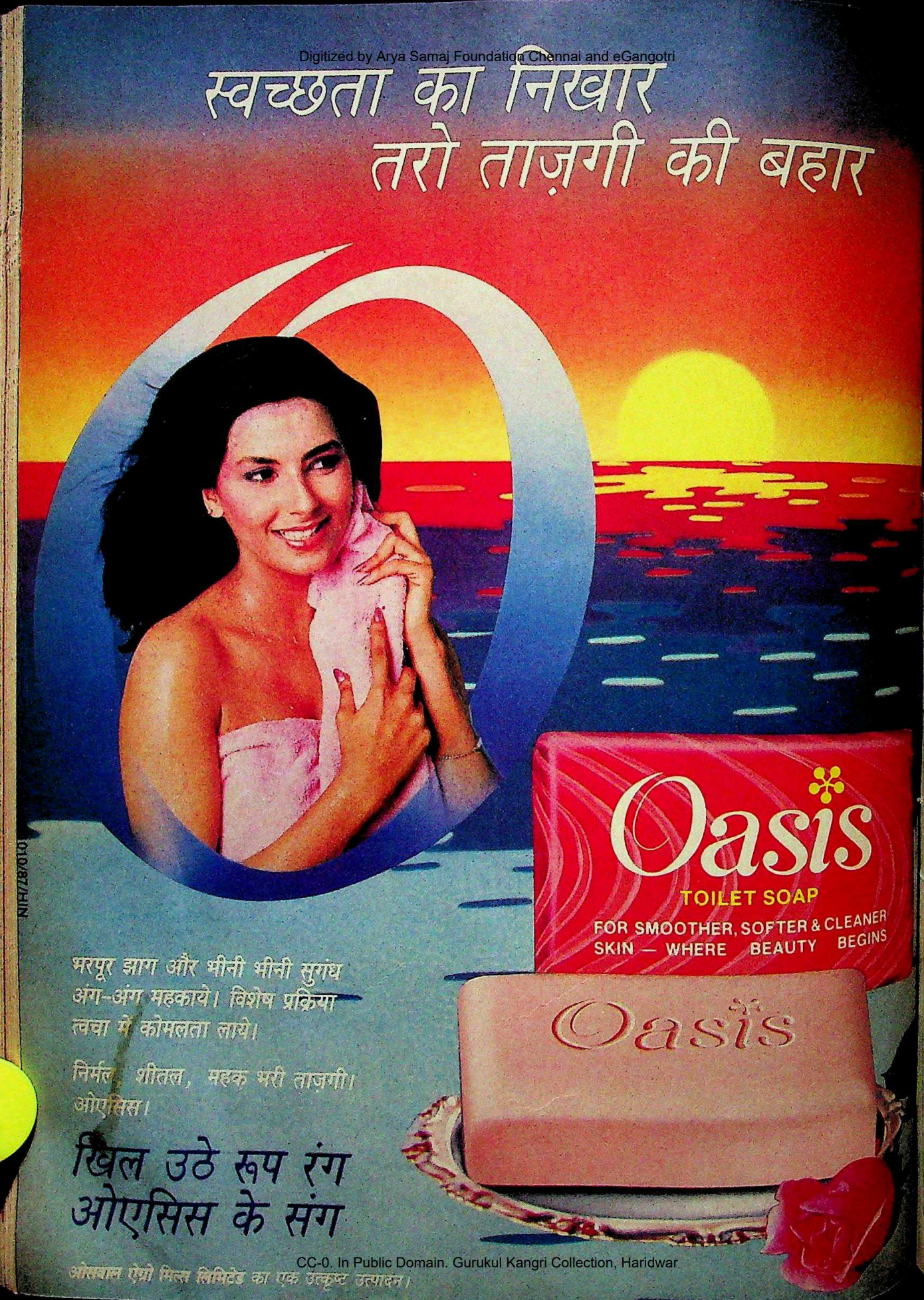

भरपूर झाग और भीनी भीनी सुगंध
अंग-अंग महकाये। विशेष प्रक्रिया
त्वचा में कोमलता लाये।

निर्मल, शीतल, महक भरी ताज़गी।
ओएसिस।

खिल उठे रूप रंग
ओएसिस के संग

ओसवाल ऐग्रो मिल्स लिमिटेड का एक उत्कृष्ट उत्पादन।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इंडिया टुडे
पाक्षिक समाचार पत्रिका

वर्ष 2, अंक 11 1-15 अप्रैल, 1988

प्रधान संपादक: अरुण पुरी
वरिष्ठ संपादक: प्रभु चावला

लिविंग मीडिया इंडिया प्रा. लि., एफ-14, कनिष्टेंट हाउस, कनाट प्लेस, नई दिल्ली के लिए अरुण पुरी द्वारा संपादित और प्रकाशित तथा थॉमसन प्रेस इंडिया लि. फरीदाबाद, हरियाणा में मुद्रित.

संपादकीय कार्यालय:
लिविंग मीडिया इंडिया प्रा. लि., एफ-14/15, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001. फोन: 331 5801-4, टेलेक्स: 31-61245 INTO IN, तार: लिवमीडिया नई दिल्ली.

मुख्य सर्कुलेशन कार्यालय:
इंडिया टुडे सर्कुलेशन मैनेजर, एफ-14, कनिष्टेंट हाउस, कनाट प्लेस, मिडल सर्कल, नई दिल्ली-110001. फोन: 3313076-8, टेलेक्स: 31-62634 INTO IN, तार: सर्कुलेट, नई दिल्ली.

मुख्य विज्ञापन कार्यालय:
28 ए और बी, जॉली मेकर चैंबर-2, नरीमन पाइंट, बंबई-400021. फोन: 2026152, 2029326, 2029435, टेलेक्स: 11-5373 THOM IN, तार: लिवमीडिया बंबई.

क्षेत्रीय विज्ञापन कार्यालय:
के-9, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001, फोन: 3325378, 3323576, 3321323, 3321273; टेलेक्स: 31-62124 THOM IN, तार: लिवमीडिया, नई दिल्ली; फागुन चैंबर्स, 26 कमांडर-इन-चीफ रोड, मद्रास-600105. फोन: 477188, 477770, टेलेक्स: 041-6177 INTO IN, तार: लिवमीडिया, मद्रास; 74/1, सेंट मार्क्स रोड, बंगलूर-560001. फोन: 568448, 579037, 579089, टेलेक्स: 0845-2217 INTO IN, तार: लिवमीडिया, बंगलूर; 12-सी, एकरोस्ट 46-सी, चौरंगी रोड, कलकत्ता-700016 फोन: 445398, 447726, टेलेक्स: 021-3138 INTO IN, तार: लिवइन-मीडिया, कलकत्ता.

कॉपीराइट 1984 लिविंग मीडिया इंडिया प्रा. लि. विश्व भर में सर्वाधिकार सुरक्षित. किसी भी रूप में सामग्री की नकल प्रतिबंधित. इंडिया टुडे अनिमंत्रित प्रकाशन सामग्री को लौटाने की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता.

नेपाल में 8 रुपए

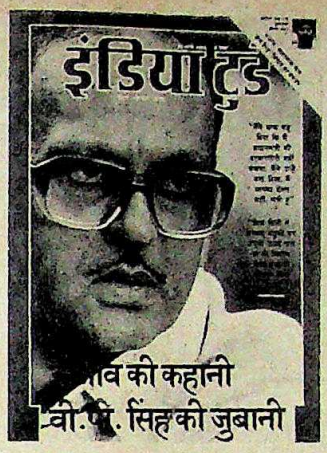

ईमानदार पर अस्पष्ट

आवरण कथा 'पेचीदा व्यक्ति, उलझे विचार' (31 मार्च) ने वी.पी. सिंह के बारे में काफी गलतफहमियां दूर कर दीं. अस्पष्ट और ढुलमुल विचार रखने वाला यह व्यक्ति देश का भला क्या नेतृत्व करेगा. नेता में ईमानदारी के अलावा राजनैतिक चातुर्य, नेतृत्व कुशलता और कूटनीतिक सूझबूझ की भी जरूरत होती है, जो कि वी.पी. सिंह में नजर नहीं आती.

—गौरव बाली, नई दिल्ली

■ इंटरव्यू में वी.पी. सिंह के राजीव पर आरोप (यदि सही हैं तो) सरकार के नैतिक मूल्यों के दिवालिएपन को दर्शाते हैं. अपने भ्रष्ट बाल-सखा— जिसका कि कोई राजनैतिक महत्व भी नहीं है—को बचाने के लिए सारे कायदे-कानून ताक पर रख देना, फिर ढिठाई से उसके साथ सपरिवार छुट्टियां बिताना क्या लोकतांत्रिक मूल्यों का मजाक और लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं? —विजय गर्ग, पटियाला (पंजाब)

■ इंटरव्यू में वी.पी. सिंह की ईमानदारी और निष्ठा तो झलकती है लेकिन भावी योजना के बारे में उनके विचार अब भी स्पष्ट नहीं हैं. फिर भला किस बूते पर वे नेतृत्व का दावा कर सकते हैं?

—विजयंत कुमार भारद्वाज, कांगड़ा (हि.प्र.)

नेकी का फल

कसौटी के अंतर्गत 'अंधी गली में लोकतंत्र' (31 मार्च) ने सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या यही सब भुगतने के लिए जनता ने अनुभवहीनता के बावजूद राजीव को इतने भारी बहुमत से जिताया था?

—सुभाष चंद शुक्ला, दिल्ली

सुर्खियों की चाह

'फिर विवाद का बवंडर' (31 मार्च) पढ़कर लगा कि ज्ञानी जी सुर्खियों में बने रहने के लिए ही ऐसे भ्रामक और धमाकेदार बयान देते रहते हैं. भारत के सर्वोच्च और गरिमामय पद पर रह चुके व्यक्ति को ऐसी हल्की हरकतें शोभा नहीं देतीं.

—बख्शीश सिंह सैनी, दिल्ली

यही होता रहेगा

'उच्च शिक्षा की दुकानदारी' (31 मार्च) पढ़कर तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ. अराजकता, अपराध, भ्रष्टाचार और शोषण का गढ़ बन चले बिहार में शिक्षा संस्थानों का यह मुनाफे वाला धंधा इसी तरह फलता-फूलता रहेगा, बेरोजगार इसी तरह शोषित होते रहेंगे. दृढ़ संकल्पों के साथ मैदान में उतरी आजाद सरकार इस दिशा में शायद ही कुछ कर पाए.

—अजय कुमार झा, दरभंगा (बिहार)

कानून सख्त हों

'सुनियोजित तस्करी का मजबूत शिकंजा' (31 मार्च) में एक गंभीर समस्या का जिक्र है. देश के युवाओं को नशे की लत से बचाने के अलावा तस्करी के मुनाफे को उन हाथों, जो न समाज के मित्र हैं न देश के हितैषी, में केंद्रित होने से रोकने के लिए सरकार को कड़े से कड़े कानून बनाकर उन पर कड़ाई से अमल करना चाहिए.

—दिलीप कुमार, वाराणसी (उ.प्र.)

■ पश्चिमी देशों की सरकार द्वारा दी गई सहयोग की पेशकश का भारत सरकार को पूरा फायदा उठाना चाहिए. मुनाफा कमाने के लिए युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रहे इन तस्करों को जितनी भी कड़ी सजा दी जाए वह थोड़ी है.

—अश्विनी कोहली, श्रीगंगानगर (राज.)

गरिमा ही नहीं

आवरण कथा 'दरबार के दमनकारी' (15 मार्च) पढ़कर लगा कि गृहमंत्री अपने पद की गरिमा को पीछे छोड़कर जी-हुजूरी की पराकाष्ठा पर पहुंच गए हैं. शायद बूटा सिंह राजीव गांधी के पैंतरे का सही आकलन नहीं कर पाए हैं. कभी अरुण नेहरू भी राजीव गांधी को ही सर्वेसर्वा मानते थे.

—कमल नयन अम्बष्ठा, गया (बिहार)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

■ लेख पढ़कर लगा कि वाकई बूटा सिंह की हैसियत राजीव गांधी के हुक्म पर खांडा चलाने वाले बधिक से ज्यादा नहीं है. बूटा सिंह के स्वतंत्र रूप से निर्णय न लेने के कारण (चाहे वह विवशता ही क्यों न हो) केंद्र-राज्य संबंध, आतंकवाद, पंजाब, गोरखालैंड आंदोलन, सांप्रदायिकता, कानून और व्यवस्था, सभी समस्याएं बिगड़ती ही गई हैं. —संजय मिश्र, बीकानेर (राज.)

■ स्टॉलिन की मौत पर आंसू बहाने वाले 'बूटा सिंह' ने जिस तरह त्रिपुरा के लोगों के खून के आंसू नजरअंदाज कर दिए हैं, उससे उनके देशप्रेम पर शक होता है.

—अविनाश वाघीकर, सेंधवा (म.प्र.)

■ दरबार के दमनकारी कब बगलें झांकते नजर आएंगे मालूम नहीं. कांग्रेस का इतिहास रहा है कि जो भी अधिक शक्तिशाली बनता नजर आए उसके पंख काट दो. अरुण नेहरू भी कभी राजीव गांधी का बायां हाथ थे. —जुगल किशोर आहूजा, श्रीगंगानगर (राज.)

कामयाब नेता

मात्र 'जी-हुजूरी' के कारण व्यक्ति के दूसरे गुणों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. आपकी रिपोर्ट से यह निष्कर्ष निकालना कठिन नहीं है कि बूटा सिंह में कम से कम निर्णय लागू करने की क्षमता तो है. अकाल तखत की 'कार सेवा' और बरनाला या जैल सिंह की तरह ग्रंथियों के सम्मुख सिर न झुकाकर बूटा सिंह ने धार्मिक कट्टरता से राष्ट्रहित को ऊपर माना. विश्वनाथ प्रताप सिंह के मामले में उनकी भूमिका विवादास्पद बेशक रही लेकिन उनकी कूटनीतिक सफलता से इनकार नहीं किया जा सकता.

—रोहित परिहार, रोहतक (हरियाणा)

सही तस्वीर

'कसौटी' में 'असंतोष का आतंक' (15 मार्च) वर्तमान भारत की सही तस्वीर पेश कर रहा था. महात्मा गांधी ने जिस पवित्र उद्देश्य के लिए सत्याग्रह आंदोलन का आरंभ किया, उसकी सफलता देख लोग हतप्रभ थे. आज उसी सत्याग्रह का मनमाने ढंग से इस्तेमाल हो रहा है जो न तो सत्य के लिए आग्रह ही है और न ही उसमें किसी प्रकार की पवित्रता बची है. सत्याग्रह पवित्र मकसद के लिए ही होना चाहिए.

—प्रणय कुमार मिश्र, जमालपुर (बिहार)

■ आपने एकदम सामयिक मुद्दा उठाया है. असंतोष का आतंक केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि स्थानीय स्तर पर भी है. सरकारी नीति समस्या को प्रारंभ में ही सुलझाने वाली नहीं रहती बल्कि आग लगने के बाद ही कुआं खोदा जाता है. भले ही सब कुछ नष्ट ही क्यों न हो जाए.

—संजय रांका, रतलाम (म.प्र.)

■ यह जानकर दुख हुआ कि देश का प्रबुद्ध युवा वर्ग राजनेताओं के बहकावे में आकर विघटनकारी प्रवृत्तियों से राष्ट्र का अहित करने में शर्म महसूस नहीं करता. एक दूसरे की देखा-देखी अब शांत और अनुशासन प्रिय तबके भी हिंसा के सहारे अपनी मांगें मनवाने पर उतर आए हैं.

—राधेश्याम, बाड़मेर (राज.)

अस्थिरता का प्रतीक

'बेकार की उलटफेर' (15 मार्च) पढ़ा. राजीव मंत्रिमंडल के ताजा फेरबदल यानी 38 महीने के अंदर 23वां और बड़े पैमाने पर 12वां फेरबदल केंद्र में इंका सरकार की अस्थिरता को जाहिर करता है. इस फेरबदल का न तो प्रशासनिक तर्क समझ में आता है न राजनैतिक. इसमें बमुश्किल ही कोई राजनैतिक मजबूती दिखती है.

—चित्रांश वीरेश दत्त, जयपुर (राज.)

■ लगता है कि राजीव ने सभी इंका मुख्यमंत्रियों से यह वायदा कर रखा है कि वह एक बार जरूर उन्हें मंत्रिमंडल में चांस देंगे और वह इसे निभाए जा रहे हैं.

—राकेश खुराना, सोनीपत (हरियाणा)

पक्का नेतृत्व

'एक लौहपुरुष का उद्भव' (15 मार्च) पढ़कर टिकैत की लोकप्रियता, नेतृत्व शक्ति और क्षमता का आभास हुआ. मेरठ में 25 दिनों तक लाखों किसानों का धरना आयोजित करके उन्होंने सरकार को किसानों के दृढ़ निश्चय, संकल्प और बुलंद इरादों से आगाह कर दिया है.

—राजन चोपड़ा, नई दिल्ली

■ इतने बड़े आंदोलन को अहिंसक रूप से चलाना टिकैत जैसे व्यक्ति के ही बूते की बात थी. लाखों किसान भी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने अपना धैर्य न खोकर संयम से काम लिया. —राजेश कुमार जैन, देहरादून (उ.प्र.)

■ महेंद्र सिंह टिकैत के जुझारू व्यक्तित्व को उजागर करता हुआ लेख भारत की किसान शक्ति के बहुआयामी प्रसार को रेखांकित करता है. उत्तर प्रदेश सरकार अगर दिल्ली में बैठे आकाओं के इशारे पर देश के अन्नदाताओं के इस आंदोलन को बर्बरतापूर्वक कुचलने की गलती करती है तो इसके भयावह परिणाम सामने आएंगे.

—शिवपूजन तिवारी, उन्नाव (उ.प्र.)

आदर्श कस्बा

'हादसे से उपजी हार्दिकता' (15 मार्च) सांप्रदायिकता फैलाने वालों के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो उन्हें कुछ सोचने को मजबूर कर देगा. आपकी पत्रिका में असम के समाचार देखकर बड़ी खुशी होती है.

—रमेश कुमार, पानीतोला (असम)

■ हमारे देश को आज होजई जैसे कस्बे की ही जरूरत है जिससे राह से भटके लोगों (आतंकवादियों) को प्रेरणा मिल सके.

—हेम टी. नायर, पाली (राज.)

■ लेख दिल को छू गया. सच कितना अच्छा वातावरण हो गया है नेल्ली का, जहां जाति-धर्म का कोई भी भेद नहीं. एक मुस्लिम भाई हिंदू बहन को अपनी सगी बहन ही मानता है. भाईचारा और मानव के प्रति कृतज्ञता कोई इन छोटे-छोटे बच्चों से सीखे.

—शेष कुमार सयान, इलाहाबाद (उ.प्र.)

खोखला चरित्र

'शहंशाह' में अभिताभ का शहंशाही चरित्र खोखला लगता है. दरअसल आम जिंदगी में अमिताभ फिल्म के दो चरित्रों में बखूबी मेल खाते हैं. पहला भ्रष्ट पुलिस अफसर जिसका रोल अभिताभ ने बखूबी निभाया है तथा दूसरा वह नेता जो जेल (अमरीश पुरी) को छुड़ाने जाता है.

—नितिन कुमार, इलाहाबाद (उ.प्र.)

■ फिल्म के एक संवाद 'इस दुनिया में गरीबों और अमीरों के लिए कानून अलग अलग हैं' के माध्यम से 'शहंशाह' ने एक कड़वी सचाई बोल दी है. कड़वी सचाई बोलने की हिम्मत कम लोग करते हैं क्योंकि ये लोग संसद में भी सच बोलने की हिम्मत कर पाते. हमारे देश की जनता बेवजह ही ऐसे लोगों को सिर पर बिठाए रहती है.

—जसबीर सिंह, चंडीगढ़ (चंडीगढ़)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

i and eGangotri

"मेरे घर में तो चाहिए, बस मिल्टन! न प्लास्टिक की गंध, न कोई झंझट!"

हरेक मिल्टन इंसुलेटेड वॉटर जग की भीतरी सतह विशेष फूड-ग्रेड लाईनिंग की होने के कारण इसमें प्लास्टिक की नागवार बू नहीं आती. तभी तो मिल्टन इंसुलेटेड-वॉटर जग से आपको मिलता है केवल शुद्ध, ताज़ा, ठंडा-शीतल, पूरी तरह दुर्गंध रहित पीने का पानी–दिन भर.

रंगीन मिल्टन वॉटर जग के रंग धूप में कभी फ़ीके नहीं पड़ते. और ये आपकी पसंद के अनुरूप कई क्षमताओं और आकारों में मिलते है. दफ़्तर या दुकान, क्लिनिक, घर या बाहर... हर जगह इस्तेमाल के लिए उपयुक्त.

❶ **गहरा ढक्कन** (कुछ ही मॉडलों में): ३ छोटे गिलास सहित.

❷ **मज़बूत लचीली बॉडी**

❸ **थर्मिल* इंसुलेशन**:
दिन-भर पानी ठंडा और ताज़ा रखता है.

❹ **विशेष फूड-ग्रेड लाइनिंग**: ताकि इसमें रखे पेय गंधरहित रहें.

❺ **माइक्रो-फ़िल्टर**:
नल के साधारण पानी को पीने योग्य शुद्ध बनाए.

** थर्मिल–पॉलीयूरेथेन फ़ोम के लिए मिल्टन द्वारा दिया गया विशेष नाम है जो एकमात्र अत्यधिक कार्यकुशल इंसुलेटिंग मटीरियल है.*

MILTONAIRE
811, Raheja Centre, Nariman Point, Bombay-400 021. Tel: 233453, 224010

MILTON

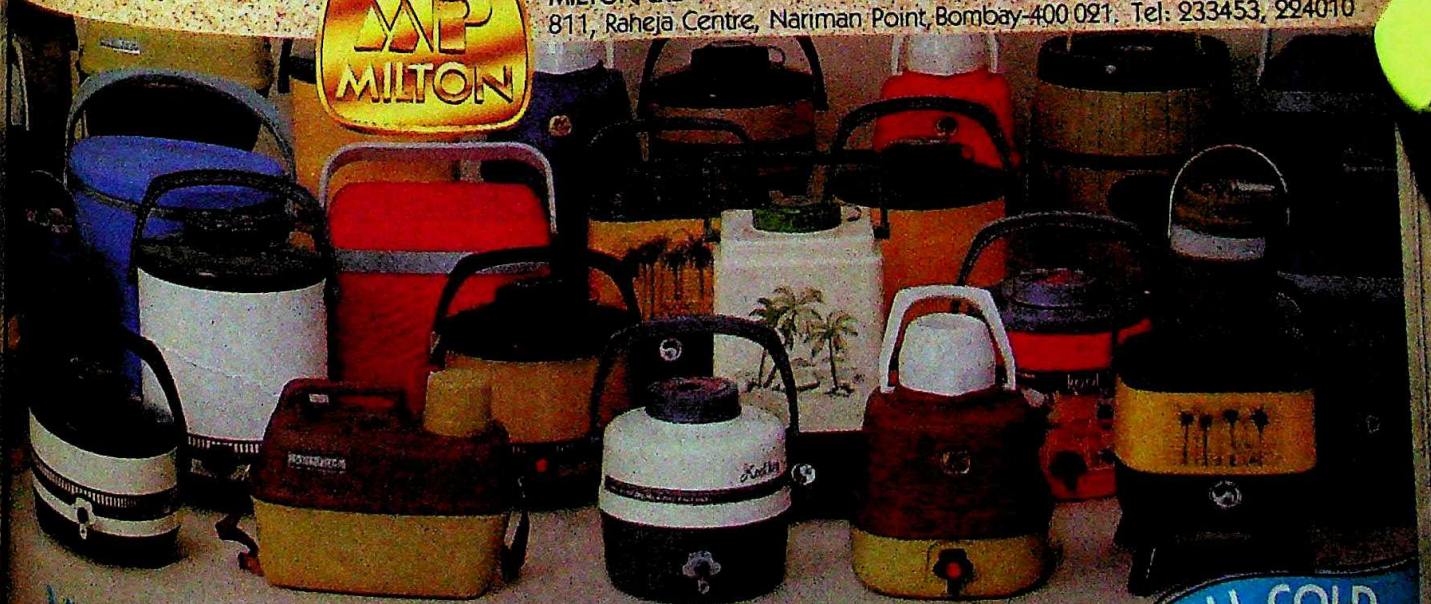

WATER JUGS FROM MILTON

ALL COLD NO SMELL

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उषा आज! उषा अब!

सुनहरे व भूरे सरताज: कोहिनूर सुपर डीलक्स, सेनेटर और नया सजीला तीन-ब्लेड पल्सर.

चमकते दमकते मोतियों से सफ़ेद. स्टैला, पल्सर, प्राइमा.

उषा के विस्तार का जवाब नहीं. विलासपूर्ण आराम भी, आसान दाम भी. हर पसंद, हर डिज़ाइन के पंखे.

और कई दूसरे आकर्षक सितारे भी–तरह-तरह के टेबिल, वॉल, कैबिन, पैडेस्टल और वेंटिलेटिंग पंखे. उषा की उत्तम तकनीक से गढ़े, दुनिया के पारखी लोगों के लिये उषा पंखे–रूप उत्तम, बिकें अधिकतम.

पल्सर डेकोरेटिव

पल्सर एक्सपोर्ट

कोहिनूर सुपर डीलक्स

कोहिनूर सुपर डीलक्स

महलों का सरताज

U S H A उषा

भारत का सर्वाधिक बिकने वाला पंखा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

स्टायलिश इरा

ग्रेविरा

GRAVIERA SUITING GR®
A Quality Product of Grasim Industries Ltd.

Karishma/BTW/36/2720 HI

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्यासे लेन-देन

कोई मांगे टैक्स कोई टैक्स भरे
लिम्का बुझाये प्यास मूड ठीक करे

जब आप इनकम टैक्स के लिए अपनी आमदनी का हिसाब लगाते-लगाते या किसी और की आमदनी का हिसाब करते-करते थक कर प्यास से बेहाल हो जायें तब आयसोटॉनिक सॉल्ट वाले किटाणुरहित लिम्का की बोतल उठायें और अपनी प्यास बुझायें.

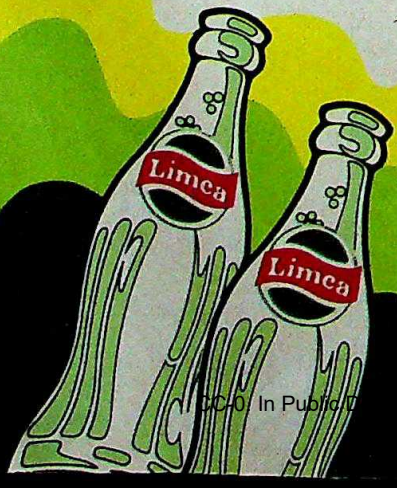

Limca®
नींबू जल-सा मज़ेदार पेय
ठंडा बर्फीला पिए-पिलाए

RADEUS/PE/L/6-88

CC-0. In Public D

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and e

नई बोतल, पुरानी शराब

परिवर्तन की उम्मीदें' (15 मार्च) पढ़ी. यह नए मर्तबान में पुराना अचार ही लगता है क्योंकि इस मंत्रिमंडल के अधिकांश सदस्य विवादास्पद हैं जिनके रहते दुबे-मंत्रिमंडल की गलतियों की ही पुनरावृति होगी. आजाद को इससे बचना चाहिए.

—नीतेश कुमार चौधरी, हजारीबाग (बिहार)

शर्मनाक हरकतें

उस्ताद रईस खां का बयान पढ़कर लगा कि वे जितने ऊंचे कलाकार हैं, उतने ही गिरे हुए इंसान भी. हिंदुस्तानियों ने किसी भी फ़नकार को उनकी काबिलियत देखकर सराहा और प्यार दिया है न कि मजहब देखकर, वरना आज भारत में इतने चोटी के मुसलमान कलाकार न होते.

—एम.जी. सोम शेखरन नायर, हजारीबाग (बिहार)

■ उस्ताद रईस खां का आरोप कि भारत में मुसलमान शास्त्रीय संगीतकारों से भेद-भाव किया जाता है, करोड़ों देशभक्त मुसलमानों के लिए शर्म की बात है. रईस खां शायद भूल रहे हैं कि पाकिस्तान में गए मुसलमानों को तीसरे दर्जे का नागरिक माना जाता है.

—मुहम्मद अयूब, रुड़की (उ.प्र.)

■ लेख पढ़कर लगा कि इनसान अपने जरा से फायदे के लिए क्या कुछ नहीं कह देता. उस्ताद रईस खां ने यह क्यों नहीं सोचा कि आज वह जो कुछ भी हैं हिंदुस्तान की मिट्टी की ही बदौलत हैं. क्लासिकल म्यूजिक को चाहने और उसकी कद्र करने वाले हिंदुस्तान से ज्यादा कहीं और नहीं हैं.

—डॉ. सैय्यद जाहिद हसन राना, पीलीभीत (उ.प्र.)

मूर्त्त जीवनानुभव

छाया लेख 'सधी थापों के थिरकते बोल' (15 मार्च) पढ़कर लगा कि अल्लारक्खा के सामने बैठकर उन्हीं के मुख से जीवन के अनुभव सुन रहे हों.

—नरेश कुमार फंगुबई, बैजनाथ (हि.प्र.)

पेप्सी से पेट भरेगा

खास रपट 'शीतल पेय में उबाल' (15 मार्च) पढ़ी. सिद्धार्थशंकर राय साहब ठीक फरमाते हैं कि पंजाब में आतंकवाद की समस्या का मूल कारण बेरोजगारी है. इसे दूर करना ही चाहिए. पंजाब में 'पेप्सी कोला' शुरू कर दिया जाए तो अनेक नौजवानों को रोजगार मिलेगा जिससे आतंकवाद की समस्या सुधर सकती है.

—हरमिंदर सिंह खोखर, पटियाला (पंजाब)

प्यादों की चाल

'अर्जुन की घर वापसी' (15 मार्च) पढ़कर लगा कि राजीव का मंत्रिमंडल शतरंज की उस बाजी की तरह है जिसमें एक नौसिखिया खिलाड़ी घबराहट में या अपने आपको होशियार दिखाने के चक्कर में बेवजह 'प्यादों' को इधर से उधर बदलता रहता है और निरंतर जीत की चाह में हार की ओर अग्रसर होता जाता है.

—कु. कल्पना धोपे, जबलपुर (म.प्र.)

घिनौनी राजनीति

'बड़ी बगावत के बगूले' (15 मार्च) पढ़कर लगा राजीव सरकार की विपक्षी सरकारों को गिराने की नीति का पूरे भारत को मूल्य चुकाना होगा. प्रधानमंत्री सुभाष घीसिंग की पीठ पर हाथ रखकर घिनौनी राजनीति खेल रहे हैं. गोरखाओं के पीछे-पीछे उत्तराखंड क्रांतिदल, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आदिवासी वन संगठन अलग राज्य बनाने की मांग लेकर आ रहे हैं. क्या राजीव उनसे भी समझौते की मंशा रखते हैं.

—सुरेशचंद्र गुप्ता मुरादाबाद (उ.प्र.)

अभिनेता में दम है

'विवाद का फल मीठा' (15 मार्च) पढ़ा. वाकई 'शहंशाह' की सफलता ने सिद्ध कर दिया है कि अमिताभ अभी भी वही सुपर स्टार है जो राजनीति में जाने से पूर्व था. अनेक आरोपों के बावजूद अभिताभ की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है.

—संदीप शर्मा, बिलासपुर (म.प्र.)

■ सिनेमा घरों की ओर खिंचती भीड़ यही दर्शाती है कि एक नेता के रूप में लोग अभिताभ बच्चन पर कितने ही आरोप लगाएं एक अभिनेता के रूप में उसकी पहचान अभी भी बरकरार है. आज भी वह नंबर वन है. 'शहंशाह' ने इसे साबित कर दिया है. उसकी फिल्मों की अभी भी लोगों को बेसब्री से प्रतीक्षा रहती है.

—आलोक कुमार सिंह, कानपुर (उ.प्र.)

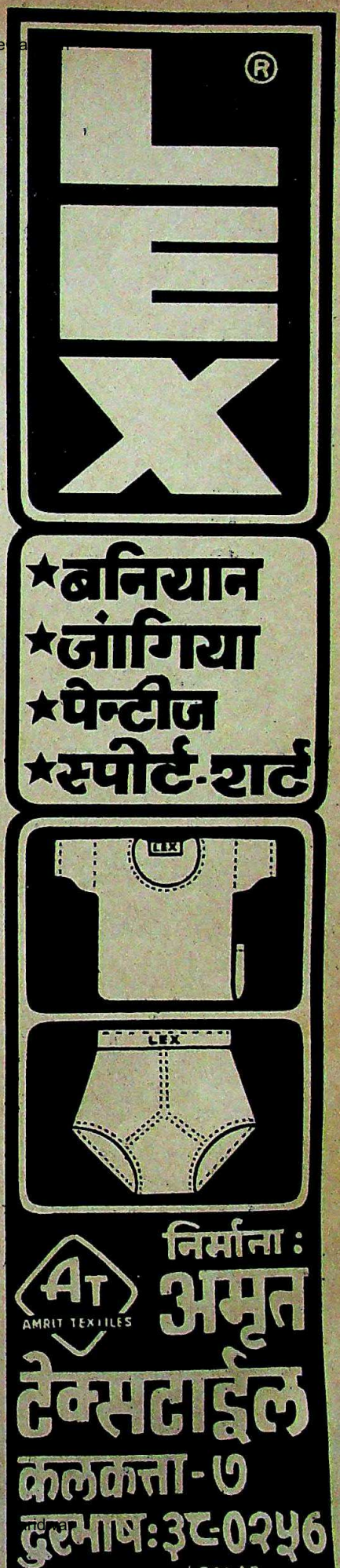

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hardwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

merino®

Aristocrat

1.5 m.m. High Pressure Decorative Laminates.

न सिर्फ देखने में शानदार ....

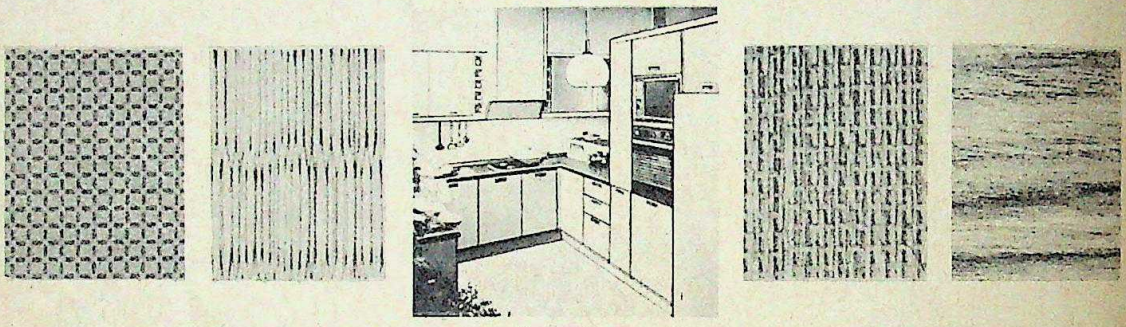

बल्कि गुणवत्ता में भी उत्तम।

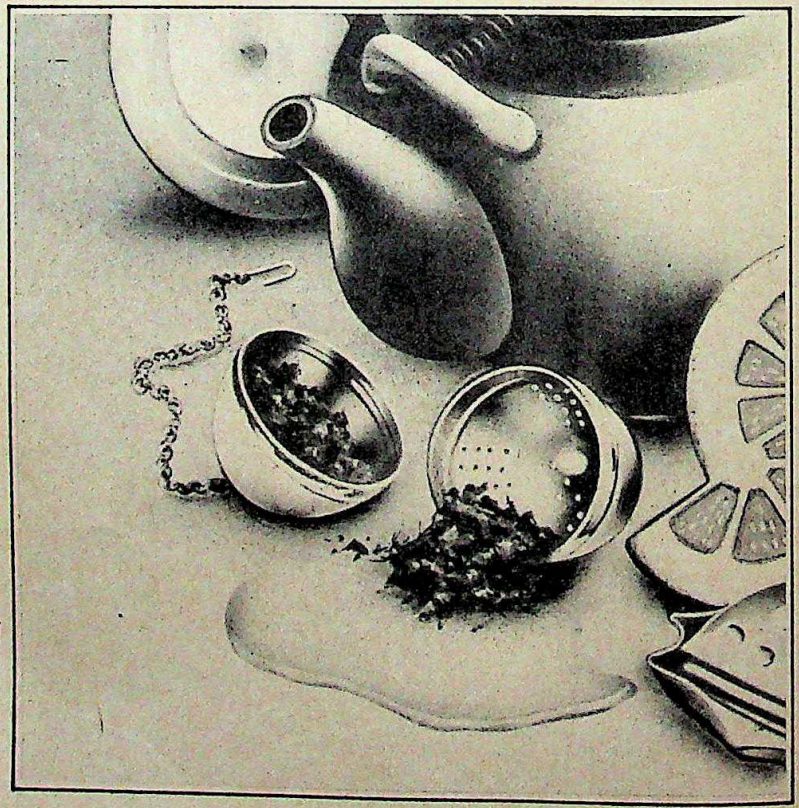

दिल को लुभा लेने वाले हाई प्रेशर सजावटी लैमिनेट्स "मैरीनो एरिस्टोक्रेट" नए-नए डिजाइनों के साथ अब आपके घर और दफ्तर को शानो-शौकत भरी सजावट देने के लिए हाजिर है। चमड़े, जूट, टैक्सटाईल और ऐसे कई खालिस विदेशी नमूनों में उपलब्ध।

धब्बों, खरोंच और पपड़ियों से छुट्टी, सिर्फ इतना ही नहीं, ये गर्मी और सीलन से भी पूरी तरह सुरक्षित है। मोटाई? एक दम उपयुक्त-1.5 मि०मी०।

जानकारी के लिए : सेन्चुरी लैमिनेटिंग कं० (प्रा०) लि० विक्रय केन्द्र: २९६९/३ चूना मण्डी, पहाड़गंज, नई दिल्ली-110055 फोन : 528845, 528784.
फोन आफिस : दिल्ली : 7110241, 7129430, बम्बई : 2044837, 2046402, अहमदाबाद : 466790, 467736, पूना : 68903 मद्रास : 563293
जयपुर : 78697/98, कलकत्ता : 449291, 440976, नागपुर : 44588, बंगलौर : 27416, कोचीन : 355726, हैदराबाद : 233490

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कसौटी

निरंकुश सत्ता की ओर

ब्रिटेन और अमेरिका में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पैदाइश के दौरान बुनियादी बात कानून का शासन स्थापित करने की जद्दोजहद थी. ऐसी व्यवस्थाओं के तहत सरकार को नहीं, लोगों को सर्वशक्तिमान माना गया. और इस संघर्ष का मूल पहलू जीने का अधिकार, स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी पाना था. भारतीय लोकतंत्र को भी उसी तरह कानून के शासन पर आधारित माना जाता है जैसे ब्रिटिश और अमेरिकी व्यवस्थाओं को. पर यहीं आकर उनकी समानता खत्म हो जाती है.

पश्चिमी लोकतंत्रों के विपरीत भारत उलटी दिशा को जाता प्रतीत होता है. उन देशों में राज्य की व्यापक सत्ता को लगातार चुनौती मिलती रहती है. पर अपने देश में राज्य राष्ट्रीय सुरक्षा कानून सरीखे अध्यादेशों और विधेयकों को पारित करवाकर व्यक्ति की कीमत पर अधिकाधिक शक्ति बटोरने में लगा हुआ है. इसका ताजा उदाहरण संविधान का 59 वां संशोधन है जिसे बड़ी उतावली में संसद के दोनों सदनों से अभी पास करवाया गया है. इससे केंद्रीय सरकार को पंजाब की बिगड़ती स्थिति से निबटने के लिए उस राज्य में इमरजेंसी लगाने का अधिकार मिल जाएगा.

रेखाचित्र: अजीत नाइनन

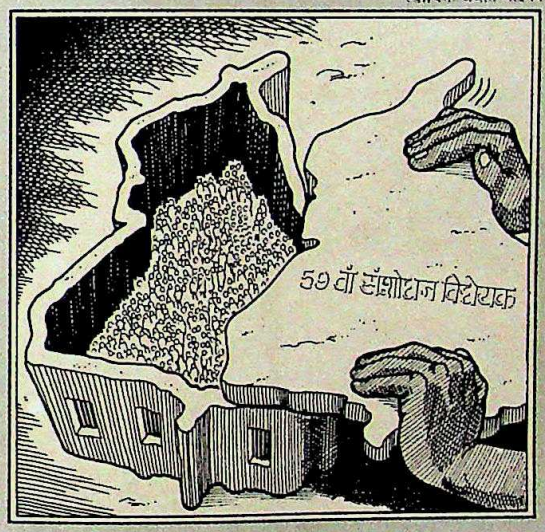

यह कानून पंजाब में आतंकवाद को रोक पाने में कितना कारगर रहेगा, इसकी असलियत सब जानते हैं. पर इतना निश्चित है कि इससे भी काम नहीं चलने वाला. पिछले पांच साल में 18 ऐसे विशेष कानून पंजाब में लागू किए जा चुके हैं जिनके तहत सुरक्षा बलों को अधिकाधिक अधिकार मिले हैं. इनमें दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन, दंड विधि संशोधन कानून, आयुध संशोधन कानून, पंजाब अशांत क्षेत्र कानून, चंडीगढ़ अशांत क्षेत्र कानून, राष्ट्रीय सुरक्षा संशोधन कानून, आतंकवादियों के लिए विशेष अदालतों का कानून, आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां निरोधक कानून जैसे अनेक अधिनियम शामिल हैं.

इन विशेष कानूनों के तहत सरकार के पास पहले से ही वस्तुतः असीम अधिकार हैं. ऐसे किसी भी शख्स को सजा दी जा सकती है जिसके सहअपराधी ने किसी पुलिस अफसर के सामने सिर्फ इकबाले जुर्म कर लिया हो, चाहे उसका सबूत न भी हो. विशेष अदालतों को बंद कमरे में मुकदमे की सुनवाई करने का अधिकार है. निवारक नजरबंदों को न्यायिक हिरासत में रखना और फिर जमानत पर भी न छोड़ना आम कायदा बन गया है. पंजाब पुलिस प्रमुख को भी फील्ड मार्शल जितने अधिकार मिल गए हैं. यही वे चाहते भी थे. पंजाब में वस्तुतः अघोषित इमरजेंसी जैसी स्थिति है.

सो नए संशोधन की जरूरत क्या थी? भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी सरीखे पंजाब के बारे में सख्त लाइन अख्तियार करने वाले लोग भी बेहद आशंकित हैं. हाल ही में उन्होंने कहा भी, "पंजाब की स्थिति कम अधिकारों की वजह से नहीं बल्कि संकल्पशक्ति की कमी से बिगड़ रही है." पर नए संशोधन के बारे में खास तौर पर घातक बात यह है कि इसने नागरिक स्वतंत्रताओं को एक दशक पीछे ला खड़ा किया है. 1978 में जनता पार्टी सरकार ने इमरजेंसी की ज्यादतियों को खत्म करने के लिए संविधान में 44 वां संशोधन किया था. लेकिन इसमें अनुच्छेद 21 को निलंबित करने के बजाय सिर्फ 'युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह' की ही स्थिति में इमरजेंसी की घोषणा का प्रावधान था. 'अंदरूनी गड़बड़ी' का इसमें कतई जिक्र नहीं किया गया क्योंकि यह शब्दावली ही अस्पष्ट थी. और फिर इन्हीं दो शब्दों की आड़ में श्रीमती गांधी ने अपनी इमरजेंसी को उचित ठहराया था.

नए संशोधन में न सिर्फ 'अंदरूनी गड़बड़ी' की स्थिति में इमरजेंसी लगाने का प्रावधान रखा गया है बल्कि केंद्र सरकार को अनुच्छेद 21 के निलंबन का अधिकार भी दिया गया है. 1976 में सुप्रीम कोर्ट में इमरजेंसी के मामले पर सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल से पूछा गया था कि अनुच्छेद 21 के निलंबन से राज्य के पास कितने अधिकार जमा हो जाएंगे. उनका उत्तर था कि उस हालत में निश्चित रैंक का कोई भी पुलिस अफसर किसी को भी पकड़कर बिना सवाल-जवाब के गोली से उड़ा सकता है.

इस संशोधन से न केवल नागरिक स्वतंत्रताओं को बल्कि प्रेस की आजादी को भी गंभीर खतरा पैदा हो गया है. प्रेस की आजादी को कुचलना इसका तात्कालिक लक्ष्य दिखता है. क्योंकि इसमें बोलने और अभिव्यक्ति के अधिकार को छीन लेने का प्रावधान है. हालांकि यह विधेयक पंजाब के लिए है, फिर भी देश का प्रेस इसके प्रभाव से अछूता नहीं बचेगा. राज्य में इमरजेंसी लगने की स्थिति में पंजाब में बिकने वाले अखबार या पत्रिका को, वहां के बारे में कुछ भी छापने से रोका जा सकता है.

राजीव गांधी की सरकार ने एक बार फिर खतरनाक रास्ते पर चलने की अपनी प्रवृत्ति को उजागर किया है. राजनैतिक तौर पर देश के दूसरे राज्यों के विपरीत पंजाब के लोगों को जीने और स्वतंत्रता के उनके अधिकार से वंचित रखना राज्य के किसी राजनैतिक समाधान के कतई हित में नहीं है. इससे सिखों में अलगाव की भावना और बढ़ेगी तथा वे आतंकवादियों के पीछे ज्यादा दृढ़ता से जा खड़े होंगे. प्रेस का गला घोंटने से भी कोई फायदा मिलने वाला नहीं है. इसका नतीजा न सिर्फ यह होगा कि अफसरों की लोगों के प्रति जवाबदेही में और कमी आएगी बल्कि लोगों को खोजपूर्ण खबरों के बजाय अफवाहें ही सुनने को मिलेंगी.

सरकार अपने अधिकार बढ़ाती रहे, यह अमूमन खतरनाक बात है. सत्ता भ्रष्ट कर देती है और निरंकुश सत्ता तो पूरी तरह भ्रष्ट करती है. ज्यों ज्यों सरकार निरंकुश सत्ता समेट रही है, भारत 'देवनगरी' कम और शैतान की पनाहगाह ज्यादा लगने लगा है.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भरिए

यह कूपन और
अपनी चहेती आवाज़ सुनिए:
बच्चे की खिलखिलाहट

हंसी-खुशी और मौज-मस्ती बच्चों के लिए उतनी ही ज़रुरी हैं जितने ज़रुरी हैं खाना-पीना और हवा. और डिस्नी टुडे लेकर आया है यही मस्ती... यही मज़े.
बस तो फिर यह कूपन भर दीजिए और हर एक को खुश कर दीजिए.

आकर्षक छूट का लाभ उठाईये.

कूपन निम्नलिखित पते पर भेजें:
लिविंग मीडिया इंडिया (प्रा.) लि.
सबस्क्रिपशन डिपार्टमेंट
थॉमसन प्रेस बिल्डिंग
पो.बॉ. न० 69, दिल्ली-मथुरा रोड
फ़रीदाबाद - 121 007 (फ़रीदाबाद)

मुझे अपने बच्चे के लिए सबस्क्रिपशन चाहिए. यह रहा मेरा सालाना सबस्क्रिपशन ☐ हिंदी रु. 78/- ☐ अंग्रेजी रु. 96/- प्रति के लिए. मैं भुगतान चैक/मनी आर्डर/डिमांड ड्राफ्ट नं. _____ द्वारा कर रहा हूँ.

कृपया प्रति निम्नलिखित नाम व पते पर भेजें:
नाम _____
उम्र _____ लिंग _____
डाक-पता _____
_____
_____
विद्यालय : _____
माता-पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर _____

कृपया भुगतान लिविंग मीडिया इंडिया (प्रा०) लि० के नाम पर बनाएं.

अब उपलब्ध हर पखवाड़े
हिन्दी और अंग्रेज़ी में

© 1987 THE WALT DISNEY CO., USA.

MILESTONES/DT/114 Hin a

● देश के डंडी मारने वाले आज दांडी यात्रा कर रहे हैं.
■ **विश्वनाथ प्रताप सिंह,** *नवभारत टाइम्स*

● जब आप गांधी जी को 'पुनर्जीवित' नहीं कर सकते तो उनके बिना यह मार्च-वार्च तो बेकार है.
■ **कमलादेवी चट्टोपाध्याय,** *संडे मेल*

● एक बात साफ कर देना चाहता हूं. मुझे पैसे देने की पेशकश न तो विपक्ष के किसी व्यक्ति ने की थी और न ही किसी असंतुष्ट कांग्रेसी ने. उन लोगों के पास पैसा कहां है?
■ **जैल सिंह,** *ऑनलुकर*

● ईमानदारी का तालमेल बेईमानी के विलय से कहीं बेहतर है
■ **हेमवती नंदन बहुगुणा,** *दैनिक जागरण*

● यह उम्मीद करना कि राजीव सरकार घोटालों से शर्मिंदा होगी ऐसा ही है जैसे वेश्या से उम्मीद की जाए कि वह अपने धंधे से शर्मिंदगी महसूस करेगी. कड़ी बातें हैं ये लेकिन क्या करूं?
■ **जॉर्ज फर्नांडीस,** *संडे ऑब्जर्वर*

● यहां (पंजाब) से निकल जाऊं तो मैं बहुत खुश होऊंगा, बहुत ही खुश...मैं कोई हीरो बनने के लिए पैदा नहीं हुआ.
■ **जूलियस एफ. रिबेरो,** *प्रोब*

● मुझे तो बहुत गुस्से में यह कहना पड़ता है कि हमारे देश में भी दक्षिण अफ्रीका वाला वातावरण जगह-जगह मौजूद है...दलित जातियों के प्रति हमारा जो आचरण है वह क्या है?
■ **नागार्जुन,** *दिनमान*

● अगर मैं चार वर्ष बाद टीम में वापस आ सकता हूं तो मैं क्यों डरूं कि चार महीनों बाद मुझे टीम से निकाला जा सकता है.
■ **नवजोत सिंह सिद्धू,** *स्पोर्टसवर्ल्ड*

● यहां (फिल्म जगत) का धंधा ही खुले बदन का है.
■ **सानिया,** *दैनिक जागरण*

● अपना कैरियर बनाने के लिए मुझे अफवाहों का सहारा नहीं चाहिए.
■ **सोनू वालिया,** *स्टार एंड स्टाइल*

● एक प्रेमकथा के लिए जरूरत होती है एक राजकपूर या दिलीप कुमार की. आज कोई हीरो है ऐसा...आज तो हर कोई अपनी मांसपेशियां दिखा रहा है और दिखा रहा है अपने बत्तीस दांत.
■ **सलीम (फिल्म पटकथा लेखक),** *रविवार*

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मंत्री पर भारी मंत्री

● गृहमंत्री बूटा सिंह अपने विरोधियों से शायद ही कभी हारते हैं. अब तक का अनुभव तो कम-से-कम यही बताता है. जिस किसी मामले में उन्होंने हाथ डाला वहां अंततः उनकी ही जय हुई है. वे हर मोर्चा फतह करते आए हैं. लेकिन इस बार वे एक अलग किस्म की लड़ाई में फंस गए हैं. नौकरशाहों

की पीठ पर लड़ी जा रही इस लड़ाई में वे अपने ही गृह राज्यमंत्री पी. चिदंबरम से मात खा सकते हैं. पिछले कुछ अरसे से चिदंबरम आंतरिक सुरक्षा का एक अलग विभाग बनाने के लिए बेहद चुस्ती से लाबीइंग कर रहे हैं. यह नया विभाग, जिसमें एक पूर्णकालिक सचिव होगा, एक शीर्ष एजेंसी के रूप में काम करेगा और खुफिया विभाग तथा केंद्रीय जांच ब्यूरो को निर्देश देगा. पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करने की जिम्मेदारी भी नए बनने वाले विभाग की ही होगी.

फिलहाल ये सभी कामकाज गृह मंत्रालय के जिम्मे हैं. लेकिन नए प्रस्ताव के मुताबिक, जिसका कि बूटा सिंह जबरदस्त विरोध कर रहे हैं, आंतरिक सुरक्षा विभाग पूरी तरह से कैबिनेट सचिवालय के तहत होगा. कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के नियंत्रण में है. बताया जाता है कि राजीव ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और विभाग के लिए एक उपयुक्त सचिव की तलाश शुरू हो गई है. यदि यह विभाग बन गया तो चिदंबरम की पदवी भी बदल जाएगी और वे आंतरिक सुरक्षा राज्यमंत्री कहलाएंगे. फिर वे गृहमंत्री की बजाय सीधे प्रधानमंत्री के मातहत हो जाएंगे.

गरमी का खौफ

● वसंत के खत्म होने और राजधानी के ऊपर धूल भरे बादलों के लक्षण दिखने के साथ सरकार ने यह खुलासा करना शुरू कर दिया है कि नई दिल्ली में इस साल पिछले साल से भी कम बिजली मिलेगी. यानी इस बार की गरमी ज्यादा कष्टदायक होगी. न केवल आम लोगों के लिए बल्कि खास लोगों, नौकरशाहों के लिए भी.

कार्मिक विभाग और विभिन्न प्रतिष्ठानों के दफ्तरों से पहले ही हिदायत जारी कर दी गई है कि बिजली बचाने के मकसद से केंद्र सरकार के दफ्तरों में एअर कंडीशनर चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. यह हिदायत संयुक्त सचिवों और अतिरिक्त सचिवों पर भी लागू होगी. और तो और, बड़े डेजर्ट कूलरों पर भी रोक लगाने का प्रस्ताव है. सरकारी अधिकारियों से कहा गया है कि गरमी में अपने

सभी कार्टून: अजीत नाईनन

दफ्तरों को ठंडा रखने के लिए पुराने देसी तरीके अपनाएं—यानी खस के परदे और झिलमिली लगवाएं. लेकिन जैसा कि नॉर्थ ब्लॉक के एक संयुक्त सचिव ने बहुत मायूसी से कहा, "यह कहना बहुत आसान है कि खस का इस्तेमाल करें. लेकिन इसके लिए भी पानी की जरूरत पड़ती है. और इस बार तो पानी भी दुर्लभ होने जा रहा है."

हैसियत स्टेनगन से

● अपनी सुरक्षा के लिए ब्लैक कैट और स्टेनगनधारी पुलिस रखना आजकल राजधानी में एक तरह की सनक बन गई है और हैसियत जताने का माध्यम भी. विभिन्न पार्टियों के सांसदों और वरिष्ठ नौकरशाहों के, जिनके नाम दूर-दराज तक किसी हिट लिस्ट में नहीं हैं, के घरों की बालू के बोरों से

किलेबंदी कर दी गई है और सुरक्षा कर्मचारी इसमें बने छेदों से आने-जाने वालों को घूरते रहते हैं. कुछ वरिष्ठ नौकरशाहों, मसलन ऑपरेशन ब्लूस्टार के बाद पंजाब के प्रशासनिक मामलों को देखने वाले अधिकारियों की सुरक्षा तो समझ में आती है लेकिन अधिकांश मामलों में तो यह समझ से परे है.

इसलिए लोगों की भृकुटियां तब टेढ़ी हो गईं जब उन्हें पता चला कि विदेश मंत्रालय के तेजतर्रार और मिलनसार सरकारी प्रवक्ता जी. पार्थसारथी ने अपने शास्त्री भवन कार्यालय के बाहर एक बंदूकधारी गार्ड तैनात करवा लिया. वे जहां भी जाते, गार्ड भी उनके साथ जाता. लेकिन उनका पद कुछ खतरनाक है भी. पार्थसारथी कई मुद्दों, खासकर श्रीलंका के मामले में सरकारी प्रवक्ता हैं. इस हैसियत से उन्होंने जो बयान दिए उससे तमिल मुक्ति चीते नाराज हो गए. उन्होंने हाल ही में पार्थसारथी को एक धमकी भरा पत्र भेजकर अपनी इस नाराजगी का इजहार भी किया. लेकिन पार्थसारथी जरा भी विचलित नहीं हुए. वे श्रीलंका समेत विभिन्न मुद्दों पर अपने बेबाक बयान देते ही रहे हैं. उनके साथ सफेद कपड़ों में सशस्त्र पक्का निशानेबाज जो होता है.

खानापूरी समिति

● बोफोर्स घोटाले की जांच कर रही संसदीय समिति रहस्य की तह तक पहुंचना तो दूर, अभी वहीं अटकी है जहां कई महीने पूर्व अपने गठन के समय थी. लगता है यह गरिमामय समिति बिना कुछ किए धरे अपना कार्यकाल बढ़वाने और मनों कागजी खानापूरी के चक्कर में ही पड़ी हुई है. रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी रटे-रटाए सवालों के रटे-रटाए जवाब तैयार करने में खास तौर पर व्यस्त हैं. खुफिया विभाग के गुप्तचरों को विदेशी बैंक खातों का पता लगाने के लिए पनामा जैसी सुदूर कई जगहों पर रवाना किया गया. इन गुप्तचरों ने समिति को एक भारी-भरकम रिपोर्ट भी सौंप दी. लेकिन कुल मिलाकर उजागर कुछ नहीं हुआ है.

समिति के सदस्य सवाल पूछने में माहिर हैं, ऐसा सूत्रों का कहना है. लेकिन उन्हें उपयुक्त शोध-

कर्ताओं का मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है इसलिए वे अक्सर भटककर ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका मूल विषय से कोई वास्ता नहीं होता. मसलन, समिति ने जनरल के. सुंदरजी से पूछताछ की जिसका ब्यौरा कई पन्नों में है. लेकिन सूत्रों के अनुसार इनमें से आधे से अधिक प्रश्नों का बोफोर्स घोटाले से किसी तरह का सबंध ही नहीं है.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सुनहरी बेगम

■ तस्करों और कस्टम विभाग के जासूसों के बीच चलने वाली आंख मिचौनी एक ऐसा खेल है जो आए दिन रूप बदलता रहता है. कस्टम विभाग की आंखों में धूल झोंकने के लिए तस्कर बिरादरी

सभी कार्टून: अनिल शर्मा

आए दिन अजीबो-गरीब हथकंडे अपनाती है. उधर कस्टम जासूसों के कारनामें भी ऐसे कि तू डाल-डाल तो मैं पात-पात.

पिछले दिनों बंबई के अंतर-राष्ट्रीय सहार हवाई अड्डे पर उतरने वाले यात्रियों में दो पाकिस्तानी महिलाएं भी थीं. विमान से उतरकर आने वाले यात्रियों की कस्टम विभाग जांच कर रहा था. परंपरा के अनुसार महिलाओं की जांच नरमी से की जाती है. इसलिए इन दो महिलाओं के सामान की भी सरसरी तलाशी ली गई और उन्हें मेटल-डिटेक्टर दरवाजे में से जाने को कहा गया. मेटल डिटेक्टर ने तो महिलाओं को 'ग्रीन सिगनल' दे दिया लेकिन एक कस्टम अधिकारी को शक हो गया. वह यह देखकर हैरान हो रहा था कि महिलाओं के चेहरे पर तो आत्म-विश्वास कायम था पर उन दोनों देवियों की चाल सामान्य नहीं थी.

शक दूर करने के लिए दोनों यात्रियों को रोककर नए सिरे से उनकी जांच की गई. मेहनत रंग लाई और कस्टम अधिकारी यह जानकर दंग रह गए कि दोनों महिलाओं ने अपने शरीर के अंदर सोने की छोटी-छोटी छड़ें छिपायी हुई थीं. बाद में जब डॉक्टर की मदद से इस सोने को बरामद किया गया तो पकड़े गए माल की कीमत लगभग सात लाख रुपए निकली.

जादूभरी डाक

■ रेल विभाग और डाक विभाग की कार्यकुशलता की महिमा से भला कौन परिचित नहीं होगा. इस बारे में इतने किस्से हैं कि पूरा पुराण लिखा जा सकता है. पिछले दिनों एक व्यक्ति के नाम चौकीदार के पद पर नियुक्ति का ऐसा पत्र आया जो अपने दफ्तर से 12 साल पहले चला था. लेकिन दुर्भाग्य से चौकीदार बनने का इच्छुक व्यक्ति 10 साल पहले ही खुदा के घर के लिए रवाना हो चुका था. ऐसे किस्से भी आए दिन सुनने को मिलते रहते हैं कि पार्सल पाने वाले के हाथ केवल डिब्बा ही पहुंचा जबकि भीतर का माल रास्ते के किसी डाक कर्मचारी के घर पहुंच गया. मगर पिछले दिनों श्रीनगर में डाक विभाग ने एक व्यक्ति के सामने जो अजूबा पेश किया वह किसी जादूगर की करामात से कम नही था. वहां के सुनील वर्मा को अपने पिता का पत्र मिला जिसमें लिखा था कि एक पार्सल में उसके लिए एक कोट रवाना कर दिया गया है. कुछ दिन बाद ही यह पार्सल अपने गंतव्य तक जा पहुंचा लेकिन वर्मा साहब यह देखकर दंग रह गए कि भीतर का कोट बदलकर स्वेटर बन चुका है. इस पर डाक विभाग से संपर्क करने पर पहले तो यही बताया गया कि मामले में विभाग कुछ नहीं कर सकता. लेकिन जब बात

ऊपर के अधिकारियों तक पहुंचाई गई तो विभाग जांच के लिए राजी हो गया. इन दिनों ऐसे कर्मचारी की खोज जोरों पर है जो पार्सल को खोले बिना ही जादू के जोर पर कोट को स्वेटर में बदल देता है.

आगे कुआं पीछे अफसर

■ यह किस्सा पंजाब के एक सरकारी मिडल स्कूल के अध्यापकों का है जो आतंकवादियों के हाथ से तो बच निकले पर अफसर के हाथों ऐसी पटखनी खा बैठे कि उन्हें छठी का दूध याद आ गया.

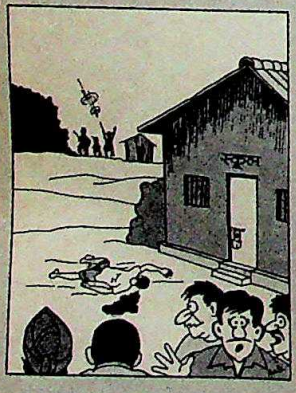

हुआ यह कि 27 फरवरी की सुबह अमृतसर जिले के गठौल गांव के स्कूल पर राइफलों से लैस आतंकवादियों ने धावा बोला और कक्षाओं में जाकर अध्यापकों की खोज शुरू कर दी. पर संयोग कुछ ऐसा रहा कि बरसात के कारण अध्यापक रास्ते में ही फंसे रह गए और आतंकवादियों के हाथ पड़ने से बच गए. आतंकवादियों ने भी अपनी खीझ मिटाते हुए स्कूल के चौकीदार को झोंपड़ी से बाहर घसीटा और उसे गोली से उड़ा दिया. आतंकवादियों के वापस जाने के कुछ देर बाद ही बरसात में भीगते अध्यापक भी वहां आ पहुंचे. स्कूल आकर जब उन्हें पूरे कांड की खबर मिली तो वे स्कूल से हफ्ते भर की छुट्टी का आवेदन देकर उलटे पांव घर लौट गए.

बाद में उन्होंने इस मामले को ऊपर तक ले जाने और बड़े अधिकारियों के सामने सुरक्षा प्रबंध करवाने की मांग पेश करने का फैसला किया. एक वरिष्ठ अधिकारी ने पहले तो उनकी बात ध्यान से सुनी और आश्वासन दिया कि विभाग उनकी मांग पर गंभीरता से विचार करेगा. लेकिन इससे पहले कि अध्यापक विदा लेते अफसर ने झट से उन्हें इस बात की सफाई देने का नोटिस जारी कर दिया कि वे उस दिन स्कूल देरी से क्यों आए?

बंदर की मर्दानगी

■ अपने मालिक की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा देने वाले कुत्ते और घोड़े के दर्जनों किस्से सुने जा सकते हैं. लेकिन ऐसा बहुत कम सुनने में आता है कि मदारी की डुगडुगी और डंडे के इशारे पर नाचकर और उछलकूद दिखाकर लोगों का मन बहलाने वाला बंदर भी ऐसा करतब कर दिखाए. पिछले दिनों रांची के निकट एक बंदर ने अपनी जान पर खेलकर ऐसा कमाल कर दिया और बदले में देश भर के अखबारों की सुर्खियों में नाम कमाया.

रांची के निकट लक्ष्मेश्वर कस्बे में एक मदारी खेल तमाशा दिखाने के बाद एक पेड़ के नीचे जा बैठा और अपने बंदर को पेड़ से बांधकर सो गया. कुछ देर बाद बंदर ने देखा कि एक फनियर सांप झाड़ियों में से रेंगता हुआ आया और सोए हुए मदारी की ओर बढ़ने लगा. मामले की नजाकत को पहचानते हुए बंदर ने तुरंत सांप पर छलांग लगा दी. इसके बाद दोनों के बीच जो मल्लयुद्ध हुआ वह कई मिनट तक चला. सांप रह-रहकर बंदर पर लपकता और बंदर की ओर से जवाबी हमला आते ही उसकी रस्सी के घेरे से दूर हट जाता. इसी बीच आसपास तमाशाइयों की अच्छी भीड़ भी जमा हो गई पर मदारी नींद में खर्राटें भरता रहा. आखिरकार बंदर की फुर्ती काम

आई और उसने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच सांप का काम तमाम कर दिया. तब तक मदारी भी अपने चहेते का यह कारनामा देखने के लिए जाग चुका था.

—संकलन: विजय कालिया

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अतीत की अनुगूंज

बीते पखवाड़े में इतिहास के बेताल ने एक बार फिर पेड़ की ओर छलांग लगाकर यह दिखा दिया कि इतिहास को खुद को दोहराने की आदत होती है. इमरजेंसी की लपलपाती तलवार का रुख पंजाब की ओर था लेकिन विरोध पर तुले विपक्ष के मानस पर 1975 का हौआ बाकायदा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा था. हर रोज हत्याओं की खबर और आतंकवादियों के लांचरों से दागे गए रॉकेटों ने भी भिंडरांवाले के भूत को फिर से साक्षात खड़ा कर दिया.

मगर अपेक्षाकृत ताजा इतिहास से जुड़ी पहेलीदार विडंबनाओं की गूंज कहीं अधिक कचोटने वाली साबित हुई. बदनाम विन चड्ढा के पुत्र हर्ष चड्ढा की वापसी से बोफोर्स के धमाके फिर प्रतिध्वनित हो उठे. सरकारी विश्वासों के ठीक उलट इस नए तथ्य ने लोगों को चौंका दिया कि विन चड्ढा के पास, अमेरिकी ग्रीन कार्ड नाम की कोई चीज नहीं है जिसके बूते वह प्रत्यावर्तन से बच सके. और इस रहस्योद्घाटन ने सरकार के इन दावों को धूल चटा दी कि वह बोफोर्स घोटाले की तह तक पहुंच चुकी है.

द हिंदुस्तान टाइम्स

बदनाम विन चड्ढा के पुत्र हर्ष चड्ढा की वापसी से बोफोर्स के धमाके फिर से प्रतिध्वनित हो उठे

भवान सिंह

प्रशांत गजियार

इलाहाबाद में वी.पी. सिंह और अमिताभ के चुनावी टकराव के परिणामों पर ही इंका और विपक्ष दोनों की किस्मत का वारा-न्यारा हो जाएगा

पूर्व राष्ट्रपति जैल सिंह ने अपने बयानों की ठोकर से एक भूले-बिसरे विवाद की धूल फिर हवा में उछाल दी और अगली ही सांस में बयान से मुकर कर अपनी विश्वसनीयता पर भी प्रश्नचिन्ह लगवा लिया. पर यह उस विवाद को फिर से जीवित कर देने के लिए काफी था जिसने कभी राजीव गांधी और भारतीय संविधान दोनों को झकझोर डाला था.

एक और जंग ने भी कौतुहल के नए दौर में चरण रखा. इलाहाबाद उपचुनाव में अभिताभ बच्चन के खिलाफ वी.पी. सिंह द्वारा मैदान में उतरने की संभावनाओं ने उत्सुकता चरम पर पहुंचा दीं लेकिन यह दांव बहुत ऊंचा रहने वाला है क्योंकि इस मुठभेड़ के परिणामों पर ही इंका और विपक्ष दोनों की किस्मत का वारा-न्यारा हो जाएगा. खास तौर से इस परिणाम पर ही तय होगा कि मध्यावधि चुनाव होंगे या नहीं. दोनों खेमों ने जंग की तैयारी शुरू कर दी है.

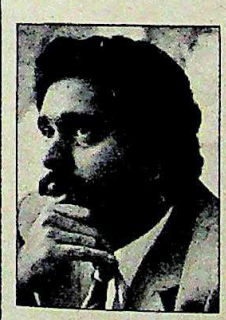

आर.पी. गोयनका और विजय माल्या जैसे उद्योगपतियों के यहां अचानक मारे गए छापों से वी.पी. सिंह के जमाने की याद ताजा हो गई

कर चोरी पकड़ने के लिए मारे गए छापों ने भी वी.पी. सिंह के जमाने की यादों को फिर ताजा कर दिया. आर.पी. गोयनका और विजय माल्या जैसे उद्योगपतियों के यहां अचानक छापे मारे गए. प्रधानमंत्री ने भी संसद में यह बयान देकर बड़ी कंपनियों को असमंजस में डाल दिया कि छापे सरकारी नीति के तहत ही मारे गए हैं.

प्रमोद पुष्करणा

पंजाब में इमरजेंसी लगाए जाने के लिए संविधान संशोधन के प्रस्ताव ने जैसे इतिहास के दोहराए जाने की आशंका जगा दी

पखवाड़े के दौरान जिस तरह हड़तालों ने देश को झकझोरा वैसा काफी अरसे से नहीं हुआ था. न केवल वकीलों बल्कि कोयला, इंडियन एअरलाइंस और दिल्ली परिवहन जैसे नाजुक हलकों में भी हड़ताल का नारा गूंज उठा. इसके अलावा विपक्ष के आह्वान पर हुए भारत बंद की विवादास्पद सफलता ने भी संकेत दिया कि औद्योगिक क्षेत्र में भूचाल आने ही वाला है.

उधर खेलों ने भी अपने हिस्से की गोलाबारी करके इस क्रम में अपना योगदान किया. भारत ने तेल अवीव में इजराएल के साथ डेविस कप मैच खेलने से इनकार कर दिया दक्षिण अफ्रीका वाले मामले की तरह इस बार भी भारत को तीन साल तक निष्कासन की कीमत चुकानी पड़ सकती है. इसका मतलब अमृतराज युग का खात्मा होगा.

लेकिन इतिहास को दोहराने के मामले में सबसे महत्वपूर्ण घटना पंजाब में इमरजेंसी लागू किए जाने के लिए संविधान संशोधन की थी. ज्यों ही यह संशोधन कानून बनेगा, सत्ताधारी दल के सुभीते पर दूसरे किसी भी राज्य में इसे दोहराने का रास्ता खुल जाएगा. एक विपक्षी नेता की टिप्पणी सटीक ही थी कि कुछ नए संशोधन और हुए तो नए संविधान और मूल संविधान में कोई खास समानता नहीं रहेगी. —दिलीप बॉब

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

किस्सा राजीव की कुर्सी पलटने की कोशिश का

सच या झूठ?

► *क्या पूर्व राष्ट्रपति जैल सिंह को पिछले साल राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए बड़ी भारी रकम देने की पेशकश की गई थी?*

► *क्या राजीव का तख्ता पलटने के लिए विपक्ष ने जैल सिंह से मिलकर कोई साजिश रची थी?*

► *क्या विश्वनाथ प्रताप सिंह, जनमोर्चा के उनके सहयोगी और समाचार माध्यम के कुछ तबके इस साजिश में शामिल थे?*

► *राजीव गांधी ने षड्यंत्रकारियों को कैसे बेनकाब किया?*

विडंबना यह है कि जिस आदमी से ये सवाल जुड़े हुए हैं और जिसने राजीव गांधी को हिला देने वाले उन अहम दिनों की याद ताजा कर दी है, वही इनका ठीक-ठीक जवाब दे सकता है. वह व्यक्ति है ज्ञानी जैल सिंह. उन्हें चुनाव में फिर से खड़े होने के लिए 30 से 40 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी जैसे लापरवाह मगर सनसनीखेज बयान देकर और फिर विवाद से पिंड छुड़ाने के लिए बयान बदलकर जैल सिंह ने खुद अपना ही नुकसान किया है. बतौर राष्ट्रपति, जैल सिंह के आखिरी हफ्तों में घटनाओं का क्रम कुछ इस तरह रहा:

► *उन्होंने राजीव को चिट्ठी लिखकर वस्तुतः उन्हें झूठा कहा.*

► *फेयरफैक्स की जांच पर विवाद उठ खड़ा हुआ.*

► *वी.पी. सिंह ने एचडीडब्ल्यू पनडुब्बियों के सौदे की जांच का आदेश दिया.*

► *स्वीडिश रेडियो ने बोफोर्स के घोटालों का पर्दाफाश किया.*

► *और राजनैतिक तौर पर राजीव गांधी केरल, पश्चिम बंगाल जैसे कई राज्यों में चुनाव हार गए जिससे इंका में असंतोष भड़का.*

माहौल घोटालों और साजिश से बोझिल हो चुका था. महीनों उपेक्षा का अपमान ढोते और कटुता पाले राष्ट्रपति के लिए यह भरपूर मौका था. और जैल सिंह ने इसे हाथोंहाथ लपक लिया. इस प्रक्रिया में न तो खुद उनकी और न ही जिस पद पर वे आसीन थे, उसकी प्रतिष्ठा में कोई चार चांद लगे. वे ऐसे राष्ट्रपति हुए जिन्हें राजनीति की चालों में मजा आता था.

वरिष्ठ संपादक ***प्रभु चावला*** *उस समय परदे के पीछे जो नाटक हो रहा था उसके अधिकतर दृश्यों के प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं. उन्होंने अपने पुराने विवरणों को छानने और उस नाटक के प्रमुख पात्रों से दुबारा बातचीत करने के बाद एक-एक घटना का निश्चित ब्यौरा दिया है.*

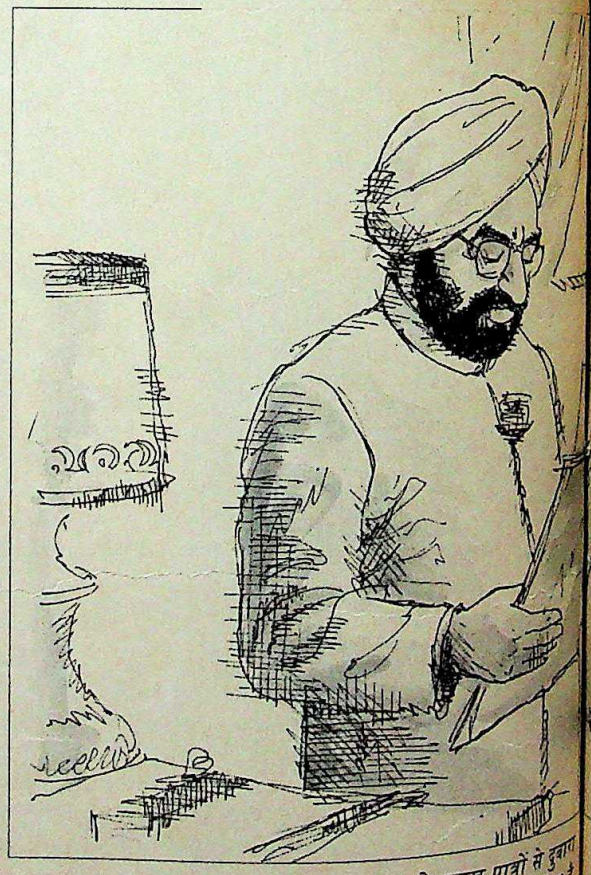

शुरुआत

4 जून 1987

स्टॉकहोम में भारतीय राजदूत भूपतराय ओझा बोफोर्स

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

स्वीडिश ऑडिट ब्यूरो की चार पेजी रिपोर्ट 'फैक्स' मशीन से प्रधानमंत्री सचिवालय को भेजते हैं. रिपोर्ट में बोफोर्स सौदे में शामिल बिचौलियों को दलाली देने की पुष्टि की गई है. प्रधानमंत्री राजनैतिक मामलों की छह सदस्यीय कैबिनेट समिति की बैठक बुलाते हैं. गृहमंत्री बूटा सिंह और दूसरे सदस्य कहते हैं कि रिपोर्ट से दरअसल सरकार को इस बात को ही बल मिला है कि सौदे में कोई भी भारतीय नेता या नौकरशाह शामिल नहीं था. एक घंटे बाद प्रधानमंत्री नई दिल्ली में मौजूद सभी मंत्रियों को बुलाते हैं और उन्हें रिपोर्ट की कॉपी देते हैं. सभी मंत्री प्रधानमंत्री का समर्थन करते हैं.

अब प्रधानमंत्री सचिवालय में वापस चलें. यहां राजीव के सलाहकार चिंतित हैं कि दूसरे दिन समाचार माध्यमों में यह रिपोर्ट छपने से विपरीत असर पड़ सकता है. लिहाजा जाफना में भारतीय वायुसेना द्वारा खाद्यान्न के पैकेट गिराने की घटना को उछालने का फैसला किया जाता है. पत्रकारों को जाफना ले जाया जाता है.

उसी दिन प्रधानमंत्री सचिवालय से राष्ट्रपति जैल सिंह के सचिव पी. वर्धन को फोन से सूचित किया जाता है कि प्रधानमंत्री एक घंटे बाद राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं. राजीव नई मर्सीडीज में समय पर वहां जा पहुंचते हैं. उनके हाथ में हरे रंग की एक फाइल है जिसमें बोफोर्स से संबंधित रिपोर्ट है. बैठक राष्ट्रपति के अध्ययन कक्ष में बिना

रेखाचित्र: अजीत नाइनन, नॉलिनी

किसी सहायक के होती है. वातावरण गंभीर है. दोनों लंबे अरसे बाद पहली बार मिल रहे हैं. इस दौरान उनके मतभेद काफी बढ़ गए हैं. लेकिन राजीव पूरा शिष्टाचार बरत रहे हैं. वे जैल सिंह को रिपोर्ट दिखाते हैं, इस विषय से जुड़े विभिन्न सवालों के जवाब देते हैं और राष्ट्रपति से यह भी कहते हैं कि शायद विन चड्ढा ने दलाली खाई है. ज्ञानी पूछते हैं, "तो अब आप क्या करने जा रहे हैं?" प्रधानमंत्री जवाब देते हैं, "हम स्वीडन की सरकार को कहेंगे कि वह कुछ करे."

राष्ट्रपति के अध्ययन कक्ष में जैल सिंह और राजीव की मुलाकात होती है. माहौल में तनाव है. राजीव कहते हैं कि बोफोर्स सौदे में शायद विन चड्ढा को दलाली मिली है. ज्ञानी पूछते हैं कि राजीव क्या कदम उठाने जा रहे हैं

इसके बाद राजीव राष्ट्रपति को श्रीलंका की घटनाओं की संक्षिप्त जानकारी देते हैं और वहां हवाई जहाजों से खाद्यान्न के पैकेट गिराने के कारण बताते हैं. फिर वे जैल सिंह को अपने घर पर 8 जून को अनौपचारिक खाने पर न्योतते हैं जिसे राष्ट्रपति मंजूर कर लेते हैं.

संकट की घड़ियां

5 जून 1987

राष्ट्रपति अपने अध्ययन कक्ष में सबेरे 10 बजे पहुंचते हैं और अपने सलाहकारों को बुलाते हैं. इनमें उनके प्रेस सलाहकार, तरलोचन सिंह, वर्धन और के.सी. सिंह शामिल हैं. घंटे भर तक जैल सिंह प्रधानमंत्री के साथ हुई अपनी बातचीत पर चर्चा करते हैं. वे ऐसा आभास देते हैं कि बोफोर्स मामले में राजीव गांधी की सफाई से वे संतुष्ट नहीं हैं. वे वर्धन को प्रधानमंत्री के नाम एक चिट्ठी का मसौदा तैयार करने का निर्देश देते हैं. इसमें वे बोफोर्स तोपों के परीक्षण की विवादास्पद रिपोर्ट और दूसरी विभिन्न तकनीकी समितियों की रिपोर्टों समेत बोफोर्स सौदे के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रधानमंत्री से मांगने की बात लिखने का निर्देश देते हैं. चिट्ठी प्रधानमंत्री के पास पहुंचती है. फिर एक बैठक होती है जिसमें रक्षा राज्यमंत्री अरुण सिंह सुझाव देते हैं कि फाइलें राष्ट्रपति को दिखाई जानी चाहिए. लेकिन उनकी बात नहीं मानी जाती.

तब विद्याचरण शुक्ल, पी. उपेंद्र और दूसरे नेता प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में बरखास्त करने की संभावना की जांच-पड़ताल करने की सलाह जैल सिंह को देते हैं. जैल सिंह काफी उत्साह दिखाते हैं. लेकिन प्रधानमंत्री को बरखास्त करने के अपने अधिकारों के बारे में वे आश्वस्त नहीं हैं. उन्हें विश्वास है कि राजीव उनकी मुट्ठी में हैं. उनकी पुरानी उदासी काफी हद तक दूर हो जाती है. वे प्रधानमंत्री पर फिकरे कसते हैं और कहते हैं, "राजनीति में आ गए हैं, पर अभी राजनीति सीखी नहीं है." जैल सिंह को सलाह दी जाती है कि वे सांसदों और मंत्रियों को अपने से मिलने के लिए बढ़ावा दें. प्रेस सलाहकार तरलोचन सिंह को निर्देश दिया जाता है कि राष्ट्रपति के साथ पत्रकारों की अधिक से अधिक बैठकें तय की जाए.

जैल सिंह उनके मुख्यमंत्रित्व काल में पंजाब के अटार्नी जनरल रहे जोगिंदर सिंह बासु को बुलवाते हैं और उनसे निर्वाचित प्रधानमंत्री

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अर्जुन सिंह यह जानने के लिए जैल सिंह से संपर्क साधते हैं कि राजीव को हटाने के लिए वे कितनी गंभीरता से और क्या कदम उठा रहे हैं. फिर वे पूरी वफादारी से इसकी जानकारी राजीव को देते हैं

को बरखास्त करने के राष्ट्रपति के संवैधानिक अधिकारों के बारे में सलाह मांगते हैं. खुद जैल सिंह राष्ट्रपति भवन के पुस्तकालय की किताबें छानने लग जाते हैं. वासु और दूसरे लोग राष्ट्रपति के अधिकारों के बारे में एक विस्तृत नोट तैयार करते हैं.

इन सबके साथ ही, राष्ट्रपति भवन में सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं का तांता लग जाता है. इनमें से कुछ नेता कहते हैं कि यदि जैल सिंह राजीव को बरखास्त करने का कदम उठाएंगे तो वे उनका समर्थन करेंगे, जबकि दूसरे कुछ नेता इसलिए वहां पहुंच रहे हैं ताकि ज्ञानी की योजना की खबर राजीव तक पहुंचा सकें.

खुफिया बनाम खुफिया

8 जून

जैल सिंह का पेट थोड़ा गड़बड़ हो जाता है और वे प्रधानमंत्री के साथ भोज समेत अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर देते हैं. जैल सिंह प्रधानमंत्री के साथ खाना वैसे भी टालना चाहते थे क्योंकि उन्होंने अभी तक अपनी रणनीति तय नहीं की थी. प्रधानमंत्री अगले राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में चर्चा के लिए ज्योति बसु समेत मार्क्सवादी नेताओं को आमंत्रित करते हैं.

इस बीच संचारमंत्री अर्जुन सिंह यह पता लगाने के लिए राष्ट्रपति से संपर्क करते हैं कि प्रधानमंत्री को हटाने की कोशिश कितनी गंभीरता से की जा रही है. यह संपर्क पंजाब की एक महिला आईएएस अधिकारी के जरिये किया जाता है जो अर्जुन सिंह के पंजाब के राज्यपाल रहते उनके साथ काम करती रही थी. यह महिला अधिकारी राष्ट्रपति के एक वरिष्ठ सहायक को सूचित करती है कि अर्जुन सिंह प्रधानमंत्री पद के लिए दावा करेंगे बशर्ते उन्हें पार्टी के बड़े पैमाने पर दोफाड़ होने की संभावना के बारे में सही जानकारी मिले.

ज्ञानी के आदेश पर उनका सहायक अर्जुन सिंह से उनके निवास पर अकेले में बातचीत करता है. अर्जुन सिंह उससे कुछ सवाल करते हैं और प्रधानमंत्री को हटाने के कदम का समर्थन करने के इच्छुक लोगों के नाम बताने का अनुरोध करते हैं. वे यह वायदा भी करते हैं कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 20 सांसद राजीव गांधी की बरखास्तगी का स्वागत करेंगे. सहायक यह कहते हुए विदा लेता है कि राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया जानने के बाद वह उनसे फिर मिलेगा.

सहायक अभी रास्ते में ही था कि अर्जुन सिंह धड़धड़ाते हुए प्रधानमंत्री के घर पहुंचते हैं और वफादारी से उन्हें अपने यहां राष्ट्रपति के सहायक के साथ हुई बातचीत की जानकारी देते हैं.

9 जून

राष्ट्रपति के पास बूटा सिंह का एक जरूरी संदेश आता है. गृहमंत्री उनसे एक असाधारण शिकायत करते हैं कि वे प्रधानमंत्री से अर्जुन सिंह (जो राजनीति में बूटा सिंह के कट्टर प्रतिद्वंद्वी हैं) के मार्फत क्यों निबट रहे हैं? राष्ट्रपति अवाक रह जाते हैं. वे इस भुलावे में हैं कि अर्जुन सिंह के साथ अप्रत्यक्ष तौर पर हुआ उनका संपर्क गोपनीय है.

बूटा सिंह ज्ञानी से मिलकर उनसे राष्ट्रपति पद से हटने के बाद की उनकी योजनाओं पर चर्चा करते हैं. वे उन्हें राजधानी में एक उपयुक्त आवास मुहैया कराने के सरकार के इरादे की जानकारी देते हैं. जैल सिंह की बेटी डॉ. गुरदीप कौर को राज्यसभा में भेजने की संभावना पर भी चर्चा करते हैं. ज्ञानी कहते हैं कि इन प्रस्तावों में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है. बूटा सिंह ज्ञानी से कहते हैं कि वे राजीव से दोस्ताना संबंध रखें क्योंकि वे (राजीव) सिखों का पूरा ध्यान रखते हैं. बूटा सिंह यह भी कहते हैं कि राजीव ने ही जैल सिंह को राष्ट्रपति और उन्हें गृहमंत्री बनाया है. जैल सिंह रुखाई से जवाब देते हैं कि

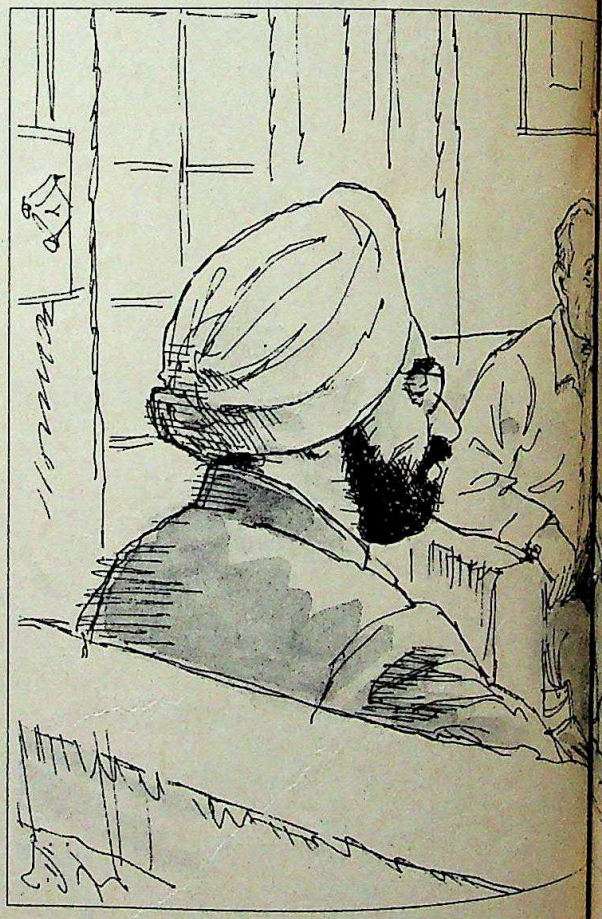

उन्होंने भी तो राजीव को प्रधानमंत्री बनाया.

फिर भी राष्ट्रपति दोबारा पद पर आने या सरकार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की संभावनाओं पर बराबर गौर कर रहे हैं. वे राष्ट्रपति भवन में 20 से ज्यादा सांसदों से मुलाकात करते हैं. दक्षिण के एक सांसद यह विचार रखते हैं कि यदि प्रधानमंत्री को बरखास्त किया जाता है तो (तत्कालीन उपराष्ट्रपति) आर. वेंकटरामन को उनकी जगह पर बिठाया जाए. एक और विचार लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाने के बारे में आता है. ज्ञानी सांसदों को सूचित करते हैं कि हरियाणा के एक पूर्व लोकदल

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सांसद मनीराम बागड़ी ने दावा किया है कि जाखड़ को कांग्रेस पार्टी के 30 सांसदों का समर्थन हासिल है.

उसी दोपहर जैल सिंह के अनुरोध पर वेंकटरामन उनसे मिलते हैं. जैल सिंह वेंकटरामन से पूछते हैं कि क्या यह सच है कि विद्याचरण शुक्ल ने प्रधानमंत्री बनने के बारे में आप से बातचीत की है और क्या आप प्रधानमंत्री बनने के लिए सहमत हैं. वेंकटरामन कहते हैं कि शुक्ल ने मजाक किया होगा. जैल सिंह वेंकटरामन से पूछते हैं कि क्या इंका उन्हें अगली बार राष्ट्रपति बनाने जा रही है. वे कहते हैं कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है.

थोड़ी ही देर बाद अरुण नेहरू पहुंचते हैं और जैल सिंह के साथ दो घंटे भर बातचीत करते हैं. दोनों बहुत सोच-समझकर बातचीत करते हैं. जैल सिंह राजीव की बरखास्तगी का सवाल उठाते हैं. लेकिन नेहरू उनसे कहते हैं कि वे जोड़-तोड़ की राजनीति में भाग नहीं लेंगे, प्रधानमंत्री को बरखास्त करने का कदम असंवैधानिक होगा. वे यह भी कहते हैं, "मैं इस सारे मामले में कुछ कर नहीं सकता. आप इस

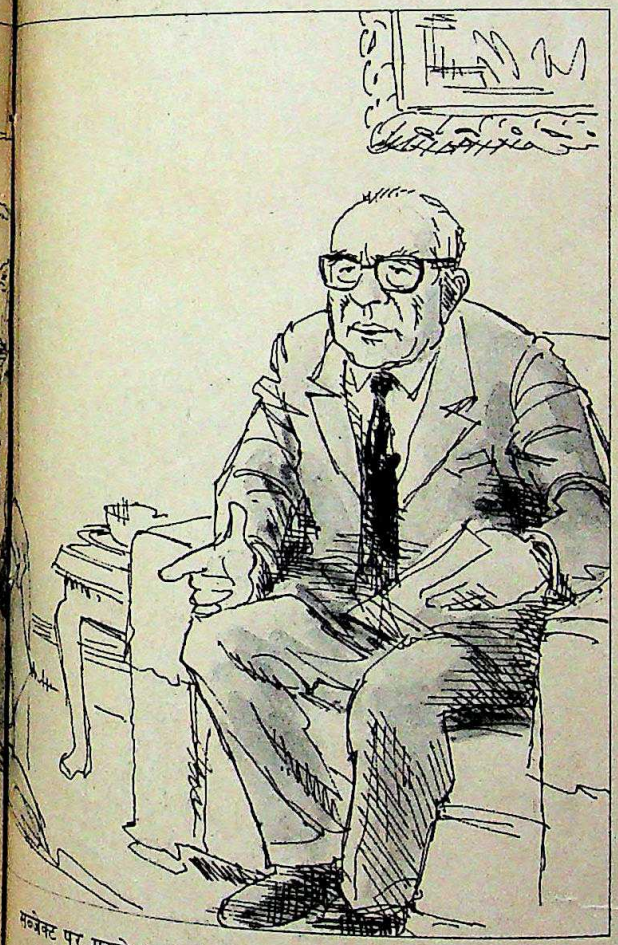

मुद्दे को प्रेसिडेंट पर मुझसे बात मत कीजिए."

इसी बीच गुप्तचर ब्यूरो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के चयन को लेकर पार्टी में संभावित बगावत की खबर देता है. प्रधानमंत्री के करीबी लोगों ने राष्ट्रपति पद के लिए बी. शंकरानंद, पुपुल जयकर और पी.वी. नरसिंह राव के नाम प्रस्तावित किए हैं. प्रधानमंत्री से शंकरराव चव्हाण, हरिदेव जोशी और जानकीबल्लभ पटनायक सहित आधा दर्जन मुख्यमंत्री कहते हैं कि यदि वेंकटरामन को राष्ट्रपति नहीं बनाया गया तो वे इस्तीफा दे देंगे.

इंका संसदीय दल का एक पदाधिकारी राष्ट्रपति से मिलता है और

वसंतदादा पाटील और जगन्नाथ मिश्र जैल सिंह से मिलते हैं. पाटील से जैल सिंह पूछते हैं कि क्या वे प्रधानमंत्री बनने के इच्छुक हैं. पाटील मुकर जाते हैं. वे कुछ ही देर पहले राजीव से मिल चुके हैं

उनसे पूछता है कि यदि मानव संसाधन विकासमंत्री पी.वी. नरसिंह राव को सत्तारूढ़ पार्टी ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं बनाया तो क्या वे राव की प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति का समर्थन करेंगे.

10 जून

आगामी राष्ट्रपति चुनाव में अपने उम्मीदवारों के बारे में सलाह-मशविरा करने के लिए जनता पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नंदमूरि तारक रामराव और माकपा महासचिव ई.एम.एस. नंबूदिरीपाद की विपक्षी समिति अपनी पहली बैठक करती है. रामराव बताते हैं कि ज्ञानी को दुबारा चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया गया तो वे इंका के दो टुकड़े करने में सफल होंगे.

दावत और दांव

11 जून

राष्ट्रपति अपनी बेटियों— डॉ. गुरदीप कौर और मंजीत कौर— के साथ दोपहर के भोजन के लिए प्रधानमंत्री के घर जाते हैं. हास-परिहास के माहौल में एक तरह का तनाव है. हर कोई एक दूसरे का मूड भांपने की कोशिश कर रहा है. राजीव राष्ट्रपति से वायदा करते हैं कि वे भविष्य में उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों और सभी महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी दिया करेंगे. ज्ञानी प्रधानमंत्री को नेहरू परिवार के प्रति अपनी वफादारी और जनता राज में की गई अपनी कुर्बानियों की याद दिलाते हैं.

14 जून

इंका संसदीय बोर्ड की बैठक में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में वेंकटरामन के नाम पर मुहर लगा दी जाती है.

मशहूर स्तंभ लेखक रजिंदर पुरी राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री के खिलाफ बोफोर्स और भ्रष्टाचार के दूसरे आरोपों को लेकर मुकदमा दायर करने के लिए उनकी इजाजत मांगते हैं. लेकिन लगता है यह कार्रवाई लगभग बेमतलब हो चली है.

बदलते तेवर

18 जून

हरियाणा चुनाव में इंका बुरी तरह मात खा जाती है. असंतुष्ट इंकाई विद्याचरण शुक्ल, माधव सिंह सोलंकी और आरिफ मुहम्मद

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जैल सिंह के चार खास सलाहकारों में एक भेदिया है जो राष्ट्रपति भवन की हर गतिविधि की जानकारी बूटा सिंह को देता है. ज्ञानी भेदिये को पहचान लेते हैं पर उसे पता नहीं लगने देते

खां के घरों पर जुटने लगते हैं. आम धारणा यही है कि अब राजीव में पार्टी के लिए वोट बटोरने की क्षमता नहीं रह गई है.

जैल सिंह अस्पताल में भर्ती देवीलाल से मिलने जाते हैं.

प्रधानमंत्री को इस घटनाक्रम की जानकारी दी जाती है और वे आनन-फानन में राष्ट्रपति भवन जा पहुंचते हैं. वे राष्ट्रपति से हरियाणा में इंका की हार और उसके कारणों पर बातचीत करते हैं. राजीव स्पष्ट रूप से बहुत निराश लग रहे हैं. 40 मिनट की बातचीत के बाद वे चले जाते हैं. फिर से प्रोत्साहित हुए जैल सिंह तुरंत इंका के दोफाड़ होने की संभावनाओं पर गौर करने का फैसला करते हैं.

प्रधानमंत्री के जाने के लगभग तुरंत बाद बूटा सिंह और राजेश पायलट राष्ट्रपति भवन पहुंचते हैं. लेकिन यह खबर फैल गई है कि प्रधानमंत्री ने इन दोनों को राष्ट्रपति को खुश रखने और उनकी योजनाओं के बारे में जानकारी बटोरने के लिए लगा रखा है. उनके मकसद को भांपकर राष्ट्रपति उनसे कहते हैं कि वे प्रधानमंत्री की बरखास्तगी की मांग पर गौर कर रहे हैं.

19 जून

स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री पर मुकदमा चलाने और उन्हें बरखास्त करने की गंभीर पहल शुरू हो गई है. छह पूर्व और वर्तमान सरकारी अफसर और वकील राष्ट्रपति के एक सहयोगी के घर पर जुटते हैं. तय होता है कि प्रधानमंत्री पर मुकदमा चलाने की पुरी की अपील पर तीन बड़ी कानूनी हस्तियों से सलाह ली जाए.

राजीव गांधी से राम जेठमलानी के रोजाना पूछे जाने वाले दस सवालों की पहली किस्त अखबारों के पहले पन्नों पर छपती है.

राष्ट्रपति की अनुमति पाने के लिए पुरी उनसे दुबारा भेंट करते हैं. राष्ट्रपति उनसे कहते हैं कि वे इसके विकल्पों पर विचार कर रहे हैं.

जैल सिंह के चार सदस्यीय खास सलाहकार मंडल में गृह मंत्रालय का एक भेदिया है. जैल सिंह को भी यह बात पता लग गई है और वे अपने कुछ संदेश बूटा सिंह को पहुंचाने के लिए सलाहकारों में शामिल उसी भेदिये का इस्तेमाल कर रहे हैं पर वे भेदिये को आभास नहीं होने देते कि उसका रहस्य खुल गया है.

एक समय श्रीमती गांधी और राजीव के विशेष सहायक रह चुके और अब राष्ट्रपति के करीबी आर.के. धवन से संपर्क साधा जाता है. धवन राष्ट्रपति के साथ करीब एक घंटा बिताते हैं और उन्हें प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई बड़ा कदम न उठाने की सलाह देते हैं.

बूटा सिंह फिर राष्ट्रपति से मिलने जाते हैं.

शाम को जैल सिंह अपने सलाहकारों की बैठक बुलाते हैं. आम राय यह बनती है कि राष्ट्रपति को राजीव के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत तभी देनी चाहिए जब या तो वे दुबारा राष्ट्रपति बनने के प्रति आश्वस्त हो जाएं या फिर उन्हें एक ऐसा प्रधानमंत्री मिल जाए जो उनके रिटायर होने के बाद उनसे बदला लेने की न सोचे.

तीन कानूनी हस्तियों में से दो की राय है कि प्रधानमंत्री को बरखास्त करना राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में है लेकिन पुरी द्वारा तैयार किया गया मामला काफी नहीं है. तीसरे कानूनदां कहते हैं कि मुकदमे की इजाजत दे दी जाए, प्रधानमंत्री को इस्तीफे के लिए मजबूर किया जाए और दूसरे प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई जाए.

उम्मीदवार

20 जून

राष्ट्रपति सत्तारूढ़ पार्टी में बड़े विद्रोह की संभावनाओं का आकलन करने का फैसला करते हैं. वी.सी. शुक्ल जैल सिंह से मिलने

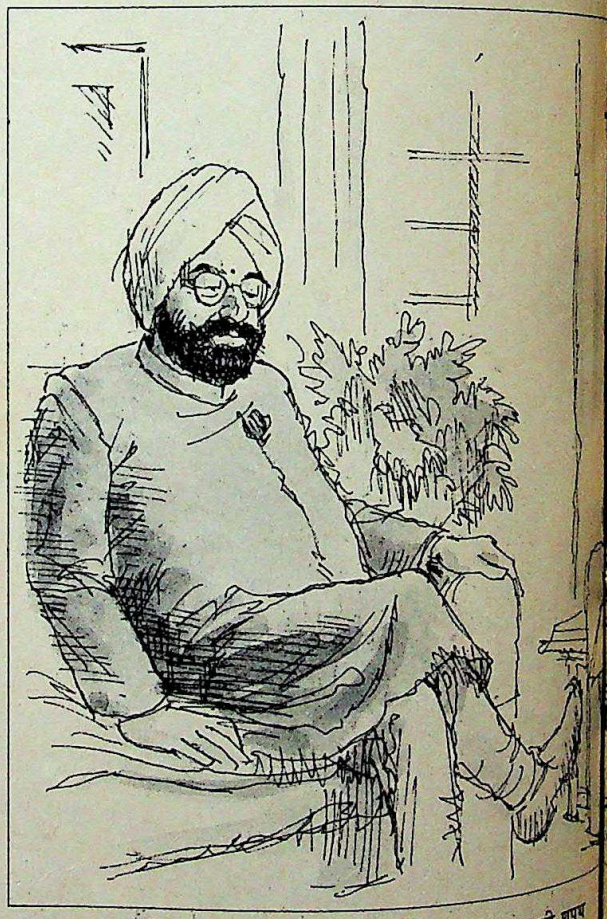

आते हैं और कहते हैं कि वसंतदादा पाटील प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के इच्छुक हैं. पाटील नई दिल्ली पहुंचते हैं और महाराष्ट्र सदन में राष्ट्रपति के बुलावे का इंतजार करते हैं.

इस बीच बूटा सिंह सक्रिय हो उठते हैं. वे राजीव को बताते हैं कि पाटील बगावत करने जा रहे हैं. राजीव और पाटील की मुलाकात होती है जो कि पहले से तय नहीं थी. फिर पाटील राष्ट्रपति भवन की ओर कूच कर जाते हैं. जैल सिंह उनसे सीधे ही पूछते हैं कि शुक्ल के कथनानुसार क्या वे प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिए तैयार हैं. बातचीत अभी जारी ही है कि जगन्नाथ मिश्र वहां पहुंच जाते हैं

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पाटील कहते हैं कि उन्होंने अपना इरादा बदल दिया है. नेतृत्व परिवर्तन के मामले में मिश्र कोई वायदा नहीं करते.

वी.सी. शुक्ल बड़ी उत्तेजना में फिर राष्ट्रपति भवन पहुंचते हैं. वे जोर देते हैं कि यदि प्रधानमंत्री को हटाया जाता है तो वे 100 सांसदों का समर्थन जुटा सकते हैं. उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ इंका सांसद नरसिंह राव का नाम सुझाते हैं पर राव से संपर्क नहीं हो पा रहा है. फिर पूर्व कानूनमंत्री अशोक सेन का नाम उछाला जाता है.

राष्ट्रपति को लगता है कि सशक्त विकल्प मात्र विश्वनाथ प्रताप सिंह ही हैं. आरिफ मुहम्मद खां को देर रात गए जगाकर कहा जाता है कि जरा वे पता करें क्या वी.पी. सिंह राष्ट्रपति भवन आ सकते हैं.

योजना यह है कि नए प्रधानमंत्री संसद भंग करने की सलाह देंगे और राजीव के खिलाफ आपराधिक मुकदमे शुरू कर दिए जाएंगे. राजीव गांधी और उनके दोस्तों, जिनमें सतीश शर्मा, अमिताभ और दिनेशदार भी हैं, के खिलाफ मुकदमों की देखरेख के लिए नए गृह सचिव और एक नए सीबीआई प्रमुख का नाम भी तय होता है. फैसला

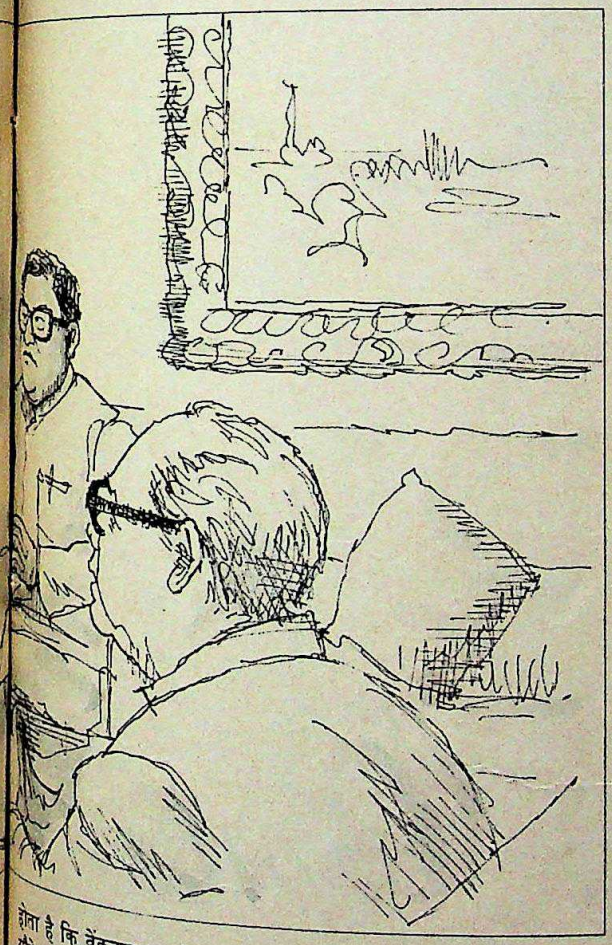

होता है कि वेंकटरामन के रक्षा मंत्रित्वकाल में जर्मन पनडुब्बियां के सौदे पर हस्ताक्षर हुए थे, उस समय का रिकार्ड ढूंढा जाए. इस योजना को अखबारों के माध्यम से प्रचारित करना भी तय होता है. इसके लिए तीन वरिष्ठ पत्रकारों— 'इंडियन एक्सप्रेस' के अरुण शौरी, एस. मुलगावकर तथा 'इम्प्रिंट' के आर.वी. पंडित का चयन होता है.

जैल सिंह वर्धन से कहते हैं कि वे राजीव को भेजी जानी वाली चिट्ठी का मसौदा तैयार कर रखें जिसमें उन्हें सूचित किया जाए कि उन्हें उनके पद से बरखास्त किया जाता है. पर वर्धन यह कहकर राष्ट्रपति का निर्देश मानने से इनकार कर देते हैं कि यह जल्दबाजी

मशहूर वकील राम जेठमलानी और स्तंभकार रजिंदर पुरी प्रधानमंत्री पर मुकदमा चलाने की इजाजत देने के लिए जैल सिंह पर दबाव डालते हैं. इस मुद्दे पर कानूनविदों में तीव्र मतभेद हैं

होगी. फिर जैल सिंह अपने सलाहकारों की खास टोली के दो सदस्यों—तरलोचन सिंह और के.सी. सिंह से चिट्ठी का मसौदा तैयार करने को कहते हैं पर वे भी इनकार कर देते हैं.

इससे पहले 'इंडियन एक्सप्रेस' के मालिक रामनाथ गोयनका और संपादक अरुण शौरी प्रधानमंत्री की बरखास्तगी के मसले पर जैल सिंह से चर्चा करते हैं और उन्हें इसके खिलाफ सख्त चेतावनी देते हैं. उनकी राय है कि यह कार्रवाई उन्हें (राष्ट्रपति को) महंगी पड़ेगी. ये दोनों राजीव के खिलाफ मुकदमा चलाने को तरजीह देते हैं.

दक्षिण बनाम वाम

21 जून

विपक्षी नेता राष्ट्रपति पद के लिए अपने उम्मीदवार तय करने आंध्र भवन में इकट्ठे होते हैं. एक तरफ वामपंथी पार्टियां अपने उम्मीदवार वी.आर. कृष्णअय्यर के लिए जोर दे रही हैं, वहीं गैर-कम्युनिस्ट पार्टियां ज्ञानी को उम्मीदवार बनाने की इच्छा जता रही हैं. उनका मानना है कि ज्ञानी सत्तारूढ़ दल के दो टुकड़े करने की स्थिति में हैं. तेलुगु देशम के नेता पी. उपेंद्र राष्ट्रपति से सीधे संपर्क साधे हुए हैं. रामराव ने एक दिन पहले जैल सिंह से बात की थी. ज्ञानी ने उनसे कहा था कि वे विपक्ष का सर्वसम्मत उम्मीदवार बनना ही पसंद करेंगे. माकपा नेता हरकिशन सिंह सुरजीत ज्ञानी से बात करते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनकी पार्टी उन्हें समर्थन नहीं देगी.

ज्ञानी चुनाव हारकर अपना पद नहीं छोड़ना चाहते हैं, यह बात उन्होंने स्पष्ट भी कर दी है. कर्नाटक के मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े; आंध्र के नंदमूरि तारक रामराव और हरियाणा के देवीलाल आंध्र भवन में घंटों बैठकर अपने भेदियों द्वारा इकट्ठा की गई सूचनाओं की कड़ियां जोड़ रहे हैं. उनके पास ऐसे करीब 50 इंका सांसदों की सूची है जो अपनी पार्टी के उम्मीदवार को हराने के लिए पाला बदल लेंगे.

प्रधानमंत्री को एक अति गोपनीय खुफिया रिपोर्ट की मार्फत बताया जाता है कि ज्ञानी अभी भी विद्रोही मूड में हैं और अगले 24 घंटों में वे कोई कार्रवाई कर सकते हैं. राजीव के निजी सचिव वी. जॉर्ज राष्ट्रपति भवन टेलीफोन करते हैं और कहते हैं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से आज अपराह्न में कभी मिलना पसंद करेंगे. राजीव ओडीसा, नगालैंड और पश्चिम बंगाल की यात्रा रद्द करते हैं.

ज्ञानी ने दूसरी अवधि के लिए चुनाव न लड़ने का मन बना लिया है. दिन में 11 बजे वे अपने सलाहकारों को अपने फैसले से अवगत कराते हैं. राष्ट्रपति वर्धन को पी. उपेंद्र से संपर्क करने को कहते हैं.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जैल सिंह बूटा सिंह से कहते हैं कि राजीव गांधी तो उनके साथ बिलकुल नौकर जैसा बरताव करते हैं. बूटा सिंह तुरंत उन्हें जवाब देते हैं कि वे इस बरताव से ही खुश हैं

1.15 बजे उपेंद्र राष्ट्रपति भवन पहुंचते हैं. राष्ट्रपति उन्हें अपने फैसले से अवगत कराते हैं. निराश होकर उपेंद्र राष्ट्रपति पद के लिए पर्चे दाखिल करने की अंतिम तारीख तक ज्ञानी से अपने विकल्प खुले रखने की गुजारिश करते हैं और उलटे पैरों आंध्र भवन लौट पड़ते हैं.

शाम 4 बजे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन पहुंचते हैं और राष्ट्रपति के साथ घंटा भर बिताते हैं. राजीव कहते हैं कि राज्याध्यक्ष को जो सम्मान मिलना चाहिए वे वह उन्हें दिया करेंगे. ज्ञानी प्रधानमंत्री को आश्वस्त करते हैं कि उन्होंने चुनाव न लड़ने का फैसला कर लिया है. दोनों में नए किस्म की सौहार्द्रता नजर आ रही है. जैल सिंह राजीव से कहते हैं, "अब तो आपको निश्चित हो जाना चाहिए कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं." राजीव जवाब देते हैं, "यह बात तो मैं पहले से ही जानता था. वे तो और लोग थे जिन्हें लगता था कि आप चुनाव लड़ेंगे." राजीव पर मुकदमा चलाने के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं होती.

उधर वामपंथी विपक्षी बैठक से वाकआउट कर जाते हैं और अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर डालते हैं. उपेंद्र ज्ञानी को मनाने दुबारा राष्ट्रपति भवन जाते हैं. लेकिन जब तक विपक्ष उन्हें सर्वसम्मति से उम्मीदवार बनाने को राजी न हो, ज्ञानी रुख बदलने को तैयार नहीं. विपक्षी नेता बहुगुणा, उपेंद्र, देवीलाल और आडवाणी ज्ञानी के प्रति समर्थन जाहिर करते हैं. हेगड़े राष्ट्रपति से मिलते हैं और बताते हैं कि उनकी पार्टी अभी भी उन्हें पूरे विपक्ष का सर्वसम्मत उम्मीदवार बनाने की स्थिति में है.

अनिच्छुक दूल्हा

22 जून

ज्ञानी पटना की अपनी यात्रा स्थगित कर देते हैं और हेगड़े के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए अपने सलाहकारों को बुलाते हैं. कुछ मंत्रियों और इंका के पदाधिकारियों समेत कई असंतुष्ट कांग्रेसियों ने जैल सिंह को भरोसा दिलाया है कि यदि वे चुनाव लड़ेंगे तो पैसा इकट्ठा हो जाएगा. विपक्षी दल भी चंदा उगाहने का वायदा करते हैं. राशि पांच करोड़ रुपए आंकी गई. इसमें एक विशेष चार्टर्ड विमान के किराए पर खर्च किए जाने वाले एक करोड़ रुपए भी शामिल हैं (चंद्रास्वामी ने 30 से 40 करोड़ रुपए की पेशकश फरवरी 1987 में ही की हो सकती है क्योंकि वे उसी समय राष्ट्रपति से मिले थे. तब जैल सिंह के दुबारा चुनाव लड़ने का मुद्दा उठा ही नहीं था).

लेकिन जैल सिंह अड़े हुए हैं कि यदि विश्वनाथ प्रताप सिंह समर्थन का वायदा करें तभी वे चुनाव लड़ेंगे. विपक्ष के दबाव का प्रतिकार करने का यही उनका तरीका है क्योंकि वे जानते हैं कि वी.पी. सिंह द्वारा उनका समर्थन करने की कोई संभावना नहीं है. उस शाम आर.वी. पंडित और एस.मुलगांवकर राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं. दोनों उन्हें आश्वासन देते हैं कि वे विश्वनाथ प्रताप सिंह को साथ खींचने की हालत में हैं. जैल सिंह उन्हें भरोसा दिलाते हैं.

पंडित और मूलगांवकर वी.पी. सिंह के घर पहुंचते हैं. वे लोग 20 मिनट तक उनसे बात करते हैं. वी.पी. सिंह जोर देते हैं कि वेंकटरामन एक अच्छे उम्मीदवार हैं और वे उनका समर्थन करेंगे. आखिरकार वे कहते हैं कि वे अपने फैसले के बारे में अगले दिन बताएंगे. अगले दिन कलकत्ता पहुंचते ही वे बयान जारी करते हैं कि वे इंका के अधिकृत उम्मीदवार का समर्थन करेंगे.

23 जून

विपक्षी दलों की राष्ट्रपति को चुनाव लड़वाने की कोशिश में कोई

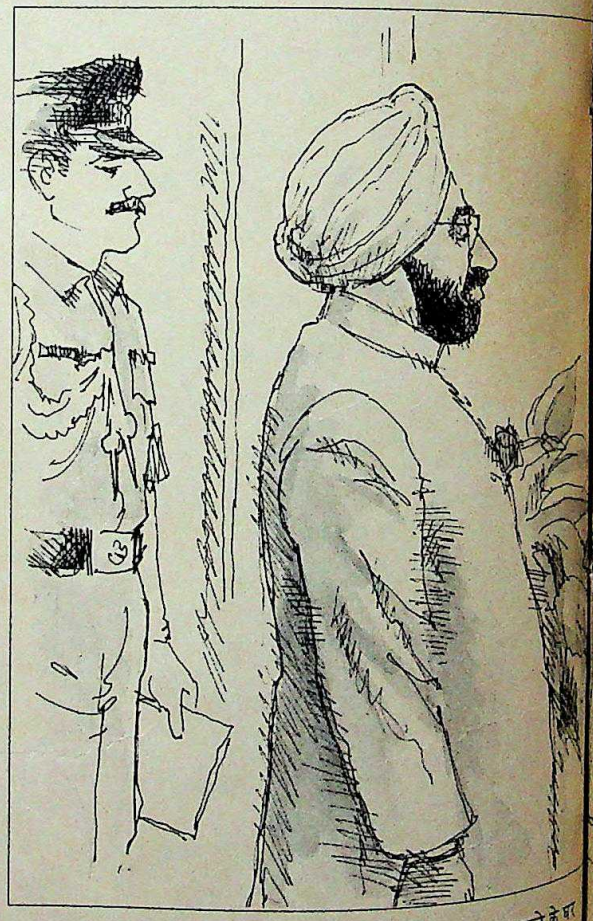

कमी नहीं आती. राजस्थान की भाजपा विधायक वसुंधरा राजे के घर एक रात्रि भोज का आयोजन होता है. इसमें हेगड़े, उपेंद्र, रामनाथ गोयनका, गुरुमूर्ति और विजयाराजे सिंधिया मौजूद हैं. वे ज्ञानी से फिर संपर्क करके उन्हें पूर्ण समर्थन का भरोसा दिलाने का फैसला करते हैं. अगली सुबह हेगड़े और उपेंद्र राष्ट्रपति से मिलने वाले हैं.

24 जून

हेगड़े देर से सोकर उठते हैं और राष्ट्रपति से नहीं मिल पाते. ज्ञानी जैल सिंह पटना के लिए रवाना हो गए हैं.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

1 जुलाई
राष्ट्रपति पश्चिम बंगाल और दूसरे राज्यों की यात्रा पर चल देते हैं, लेकिन षड्यंत्रकारी अभी भी सक्रिय हैं.

मुकदमे का दांव

2 जुलाई
राम जेठमलानी, जॉर्ज फर्नांडीस और पुरी प्रधानमंत्री के खिलाफ ताजा सबूत जुटाते हैं और उसे राष्ट्रपति के पास भेजते हैं. जेठमलानी और जॉर्ज फर्नांडीस हाल ही में स्वीडन की यात्रा करके लौटे हैं. उधर राजीव मॉस्को की यात्रा पर रवाना हो गए हैं.

4 जुलाई
राजीव को बूटा सिंह से पता चलता है कि उनके खिलाफ मुकदमे के मामले में राष्ट्रपति कानूनी माहिरों से सलाह ले रहे हैं.

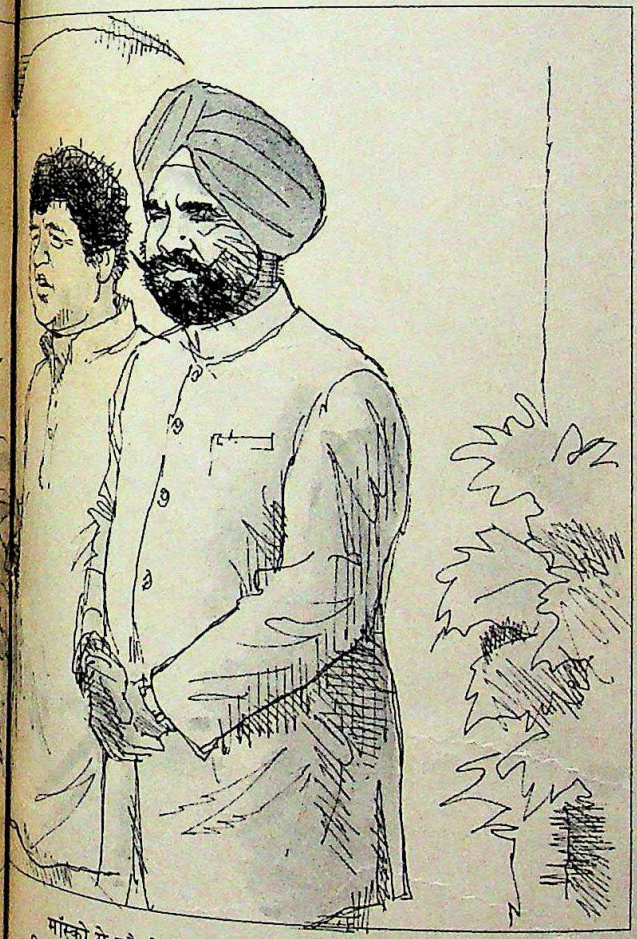

मॉस्को से लौटने के कुछ ही घंटे बाद राजीव, सोनिया, राहुल और प्रियंका पारिवारिक भोज के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचते हैं. प्रधानमंत्री सोवियत नेताओं के साथ हुई अपनी बातचीत का ब्यौरा देते हुए राष्ट्रपति के साथ घंटा भर बैठते हैं. प्रधानमंत्री के खिलाफ मुकदमे का कोई जिक्र नहीं होता.

9 जुलाई
ज्ञानी पूर्व मुख्य न्यायाधीश वाई.वी. चंद्रचूड़ को राष्ट्रपति भवन बुलाकर उन्हें वे कागजात देते हैं जो जेठमलानी और दूसरे लोगों ने

बूटा सिंह और राजेश पायलट से जैल सिंह कहते हैं कि उन्हें कमलकांत तिवारी का इस्तीफा चाहिए और यह कि माखनलाल फोतेदार को भी प्रधानमंत्री सचिवालय से हटा दिया जाए

उन्हें भेजे थे. राष्ट्रपति चंद्रचूड़ से इस बारे में राय मांगते हैं. पर वे एक दिन की मोहलत मांगते हैं. ज्ञानी एक और पूर्व मुख्य न्यायाधीश एस.एम. सीकरी और अशोक सेन से भी सलाह मांगते हैं.

11 जुलाई
राष्ट्रपति को तीनों लोगों से कानूनी सलाह मिलती है. उनमें से दो कहते हैं कि राष्ट्रपति को मुकदमा चलाने की अनुमति देने का अधिकार है पर उन्हें लगता है कि अकाट्य मामला दायर करने के लिए ये दस्तावेज ही काफी नहीं हैं. वे फैसला राष्ट्रपति पर छोड़ते हैं.

उसी शाम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से उनके रिटायरमेंट के बाद की योजनाओं पर विचार करने के लिए फिर मिलते हैं. इसमें निवास स्थान के चयन आदि पर विचार होता है.

वरिष्ठ मंत्रियों और प्रधानमंत्री के सहायकों की एक बैठक राजीव के घर पर होती है. इसमें अधिकाधिक सांसदों को नई दिल्ली बुलाने का फैसला होता है. अरुण नेहरू और आरिफ मुहम्मद खां की गतिविधियो पर खुफिया ब्यूरो की एक रिपोर्ट भी पेश की जाती है.

जवाबी हमला

15 जुलाई
वेंकटरामन राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित किए जाते हैं. वरिष्ठ पार्टी सहयोगी राजीव के घर पर इकट्ठा होकर असंतुष्टों पर जवाबी हमला करने का फैसला लेते हैं. आरिफ, नेहरू और वी.सी. शुक्ल को पार्टी से निकाल दिया जाता है.

अरुण नेहरू के आवास पर 20 से अधिक इंका सांसदों की बैठक होती है और विद्रोह का फैसला लिया जाता है.

16 जुलाई
वी.पी. सिंह प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर पार्टी और राज्यसभा से इस्तीफा देते हैं तथा राजीव पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाते हैं. पुरी जैल सिंह को एक और चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री पर मुकदमा ठोकने की इजाजत मांगते हैं.

बूटा सिंह नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के बारे में सलाह-मशविरे के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचते हैं. उनका असली मकसद यह जानना है कि क्या जैल सिंह मुकदमे के मामले को लेकर अब भी उतने ही गंभीर हैं? वे राष्ट्रपति से कहते हैं कि मुकदमा चलाने की मांग के पीछे जो लोग हैं उनकी पीठ पर विदेशी एजेंसियों का हाथ है और यह

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भी कि यदि जैल सिंह इस साजिश में एक हिस्सेदार बनते हैं तो उनकी बदनामी ही होगी.

बूटा सिंह कहते हैं कि कठिनाई के दिनों में जैल सिंह की व्यक्तिगत सुरक्षा बहुत चिंता का विषय रही है सो राष्ट्रपति भवन में सुरक्षा की जिम्मेदारी सेना से लेकर पुलिस को सौंपी जानी चाहिए. जैल सिंह बूटा सिंह का खेल समझ जाते हैं और इनकार कर देते हैं. जैल सिंह बूटा सिंह से कहते हैं कि राजीव ने उनसे (बूटा सिंह से) बहुत क्षुद्रता से बरताव किया है और यह भी कि बूटा सिंह की कोई साख नहीं है. वे राजीव के एक नौकर से ज्यादा हैसियत नहीं रखते. बूटा सिंह कहते हैं कि इस बरताव से वे खुश हैं.

सोनिया गांधी और उनके बच्चे जैल सिंह को नाश्ते में आमलेट, कटलेट और तरह-तरह की डबल रोटियां परोसते हैं. राजीव अंततः अपनी कठिनाइयों के खत्म होने से खुश दिखते हैं

17 जुलाई

इंडियन एक्सप्रेस में अजिताभ द्वारा स्विट्जरलैंड में जायदाद खरीदने के बाबत एक खास रिपोर्ट छपती है. वी.पी. सिंह बच्चन बंधुओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं.

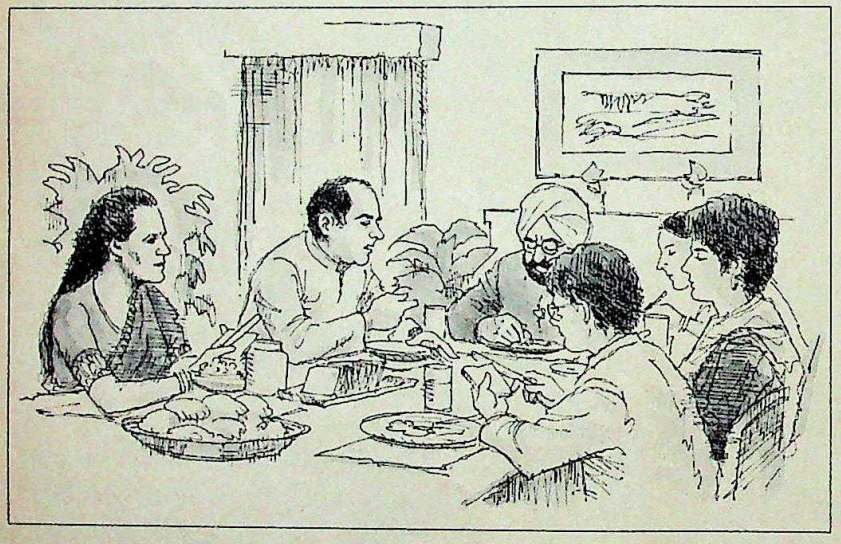

18 जुलाई

प्रधानमंत्री पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए वी.पी. सिंह को इंका से निष्कासित कर देते हैं और विदेश में अजिताभ बच्चन की गतिविधियों की जांच के आदेश देते हैं. राजीव अमिताभ बच्चन का लोकसभा से इस्तीफा भी मांग लेते हैं.

यह सनसनीखेज खबर भी मिलती है कि रक्षा राज्यमंत्री अरुण सिंह ने इस्तीफा दे दिया है.

अंतिम झटका

21 जुलाई

प्रधानमंत्री की कोठी पर एक बैठक, जिसमें उनके राजनैतिक सहायक माखनलाल फोतेदार मुख्य वक्ता है. तय होता है कि पार्टी कार्यकर्ताओं को राष्ट्रपति के खिलाफ बयान जारी करने के लिए कहकर राष्ट्रपति को बचाव की स्थिति में ला दिया जाए. शाम 4 बजे कमलकांत तिवारी पत्रकार वार्ता बुलाते हैं और अपना आरोप दोहराते हैं कि राष्ट्रपति भवन निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने की साजिश का अड्डा बन गया है. बूटा सिंह और पायलट से कहा जाता है कि वे ज्ञानी के विश्वासपात्र बने रहने की कोशिश करें.

राष्ट्रपति बूटा सिंह को सूचित करते हैं कि यदि तिवारी को मंत्रिमंडल से नहीं हटाया गया तो वे कार्रवाई करेंगे. वे फोतेदार को प्रधानमंत्री सचिवालय से हटाने की भी मांग करते हैं. जैल सिंह चेतावनी देते हैं कि यदि उनकी मांग न मानी गई तो वे वेंकटरामन के शपथ-ग्रहण समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे और खुद तिवारी को मंत्रिमंडल से बरखास्त करके ही दम लेंगे.

23 जुलाई

राष्ट्रपति की धमकी पर सलाह-मशविरे के लिए प्रधानमंत्री के घर पर तुरंत एक बैठक होती है. बूटा सिंह और प्रधानमंत्री के विशेष सचिव गोपीकृष्ण अरोड़ा तिवारी के इस्तीफे के पक्ष में हैं. पर कानूनमंत्री पी. शिवशंकर समेत दूसरे लोग राष्ट्रपति की बात मानने के खिलाफ हैं. आखिरकार राजीव तय करते हैं कि तिवारी को जाना होगा. पायलट को राष्ट्रपति से मिलकर यह बताने के लिए कहा जाता है कि मंत्रिमंडल के अगले फेरबदल में तिवारी की छुट्टी कर दी जाएगी. उन्हें जैल सिंह को यह भी बताने को कहा जाता है कि फोतेदार को प्रधानमंत्री सचिवालय से हटा दिया जाएगा.

बूटा सिंह राष्ट्रपति से तिवारी की छुट्टी करवाने का वायदा करते हैं. उसी शाम को तिवारी इस्तीफा दे देते हैं.

राष्ट्रपति कार्यालय से पुरी को चिट्ठी भेजी जाती है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने में असमर्थ हैं.

24 जुलाई

प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नाश्ते पर प्रधानमंत्री के घर मिलते हैं. कमरे में किसी को आने की इजाजत नहीं. सोनिया और उनके बच्चे राष्ट्रपति को आमलेट, कटलेट और तरह-तरह की डबल रोटियां परोसते हैं. राजनीति पर चर्चा नहीं होती. राजीव वायदा करते हैं कि वे बहुधा जैल सिंह से मिलकर सलाह लिया करेंगे.

बैठक के बाद दोनों गले मिलकर मतभेद भुलाने का वचन देते हैं.

25 जुलाई

जैल सिंह पदमुक्त होते हैं और आर. वेंकटरामन नए राष्ट्रपति के तौर पर पदभार संभालते हैं.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दुनिया एक डाक टिकट है

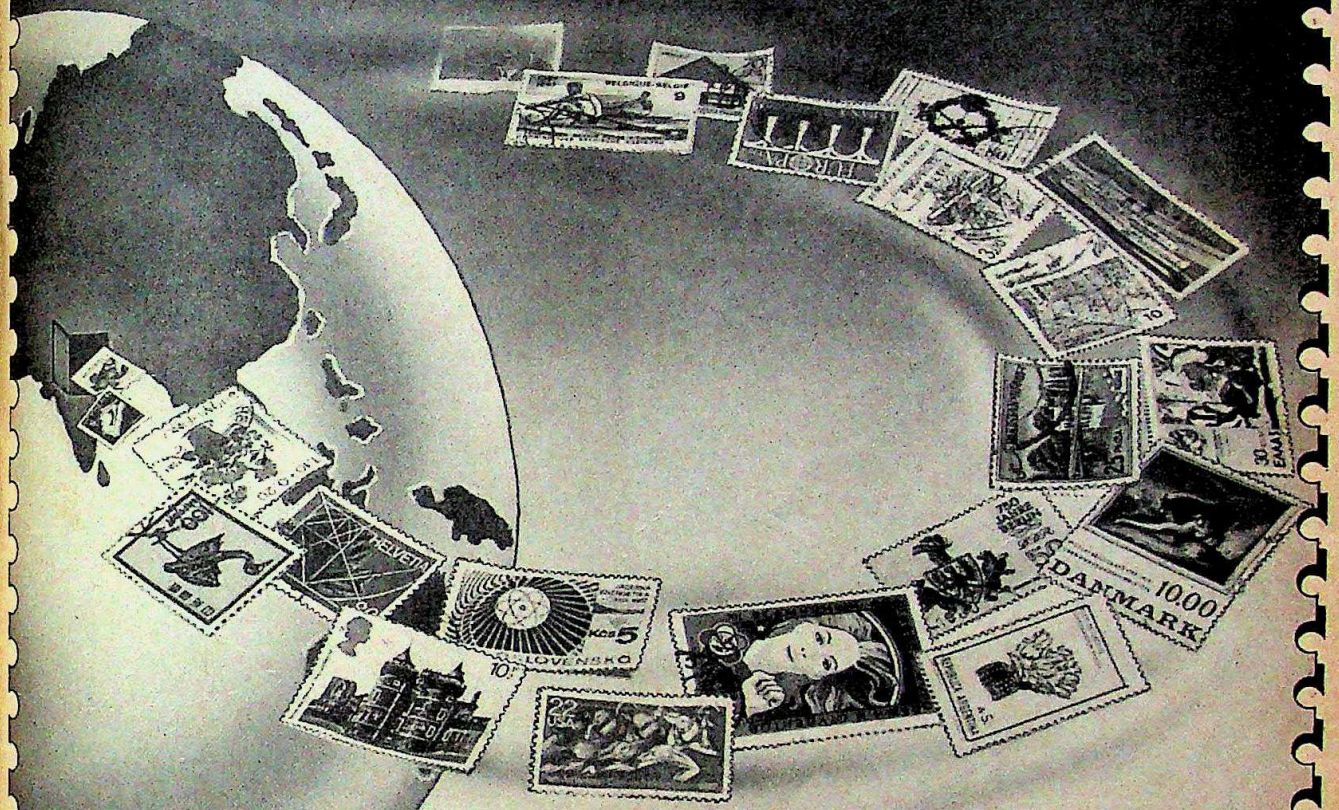

यह दुनिया, हमारी दुनिया, यह ज़मीन और इसके सभी निवासी, मनुष्य, प्रकृति और उससे जुड़ी तमाम चेतन वस्तुएं, वर्तमान और भविष्य, प्रगति, विकास, समृद्धि और उपलब्धियों की शाश्वत कथा – सभी कुछ तो प्रतिरूपित होता है दुनिया भर के हरेक देश के डाक टिकटों पर, बहुत ही सटीक और मोहक शैली में.

डाक टिकट जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है :

भारत 89

विश्व फिलैटली प्रदर्शनी

प्रगति मैदान, नई दिल्ली. जनवरी 20-29, 1989

आपके लिए यह एक अनूठा अवसर है जब आप अपने डाक टिकटों का संग्रह विश्व-भर के सुधी-प्रेक्षकों के सामने रख सकेंगे, प्रसिद्ध टिकट संग्राहकों से मिल सकेंगे, एक दूसरे को प्रभावित कर सकेंगे, विभिन्न देशों के बारे में आपसी समझ के सूत्रों को सुदृढ़ कर सकेंगे और इनसे भी बढ़कर इस धरती, यहां के मानव और सम्पूर्ण सृष्टि के सौन्दर्य से आपका साक्षात्कार हो सकेगा.

आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि :
30 अप्रैल 1988.

विस्तृत जानकारी के लिए लिए लिखें :
निदेशक, भारत 89, डाक भवन,
संसद मार्ग, नई दिल्ली-110 001.
फ़ोन : 384893, 3032440

ADVEL/DP/441

भारत INDIA 89

अपनी संग्राहक की छवि 20 वीं शताब्दी के विश्व पर अंकित करें।

डाक विभाग, भारत सरकार द्वारा, भारतीय फिलैटली कांग्रेस के सहयोग से आयोजित.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

राज्यसभा चुनाव

पुराने नेताओं का पुनर्वास

विपक्ष की ताकत बढ़ते जाने से सत्तारूढ़ दल में दहशत

प्रधानमंत्री राजीव गांधी सबको हैरत में डालने के लिए मशहूर हैं. इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया. लोगों को उम्मीद थी कि राज्यसभा चुनाव के लिए इंका के 38 उम्मीदवारों की अंतिम सूची में राजीव के दून स्कूल के कई दोस्त, रिटायर्ड अफसर और कई सक्रिय महिला नेताओं के नाम होंगे. ये सब पिछले दरवाजे से राजनीति में घुसने के लिए गोटी भिड़ा रहे थे. पर राजीव ने

प्रमोद पुष्करणा

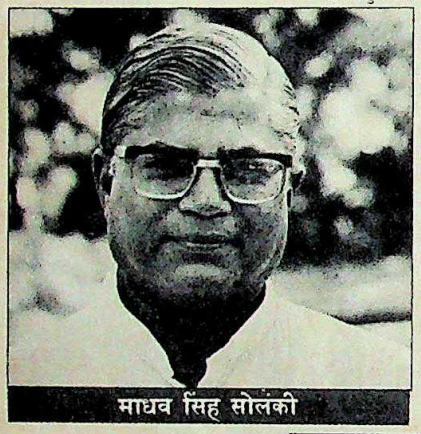

माधव सिंह सोलंकी

जगन्नाथ मिश्र

प्रकाश पांडेय

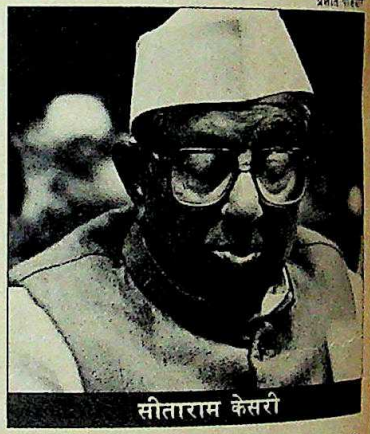

सीताराम केसरी

राज्यसभा के नामांकन का मामला नितांत राजनैतिक हथकंडे के तौर पर निबटाया. इसका मकसद पार्टी में असंतोष खत्म करना था. जाहिर है राजीव की निगाह अगले आम चुनावों पर है जिनके संपन्न होनें में 19 महीने ही शेष रह गए हैं.

असंतोष फैला सकने वाले धुरंधरों को शामिल करने के लिए वफादारी की शर्त की भी अनदेखी कर दी गई

राज्यसभा की सदस्यता का लालच देकर पार्टी ने बहुत से इंकाइयों के पुनर्वास का इंतजाम कर दिया. निवर्तमान 48 में से 19 इंका सांसदों को ही फिर से टिकट दिए गए. बाकी पर पार्टी कार्यकर्ताओं को या जांचे-परखे नेताओं को नामजद किया गया. इंका के एक उत्साही महासचिव कहते हैं, "कौन कहता है कि पार्टी गैर-राजनैतिक लोगों को तरजीह देती है? यह सूची इस बात का सबूत है कि प्रधानमंत्री सिर्फ उन्हीं को महत्व देते हैं जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया है और उसके लिए लड़े हैं."

फिर भी पार्टी में असंतुष्ट लोगों की कमी नहीं. पार्टी राज्यसभा की 38 सीटें ही पा सकती है पर उम्मीदवार 5,000 से भी ज्यादा थे. राजीव के लिए चुनाव इतना आसान नहीं था. दावेदारों में उनके करीबी दोस्त, वरिष्ठ पत्रकार और राज्यों के ऐसे धाकड़ नेता भी थे जिन्हें पिछले चार साल में किनारे लगा दिया गया था. और जब इंका संसदीय बोर्ड नामों का निबटारा करने बैठा तो फैसला करने के लिए उसके पास कोई दिशा-निर्देश नहीं थे. आखिर छोटी की गई सूची के 200 नामों में से उसने 38 लोगों को नामजद करने का फैसला किया. पैमाना यही था कि वे कांग्रेस के प्रति समर्पित और राजनीति के मैदान के तजुर्बेकार हों.

इंका संसदीय बोर्ड ने यदि इस एक नियम पर अमल किया, तो कई दूसरे तोड़ दिए. नियम था कि जो दो या उससे अधिक कार्यकाल पूरे कर चुका हो, उसे दुबारा नामजद नहीं किया जाएगा. पर स्वास्थ्य राज्यमंत्री सरोज खापर्डे और प्रतिभा सिंह को तो लगातार चौथी बार नामजद किया गया जो कि एक रिकार्ड है. जिन 24 राज्यसभा सदस्यों को दुबारा टिकट नहीं मिला उनमें 14 ऐसे थे जिन्होंने एक ही कार्यकाल पूरा किया है. यहां तक कि मंत्रियों के मामले में भी किसी नियम पर अमल नहीं किया गया. खापर्डे, कानून व न्याय राज्यमंत्री हंसराज भारद्वाज, श्रम उपमंत्री राधाकृष्ण मालवीय और पेट्रोलियम उपमंत्री रफीक आलम को फिर टिकट दिया गया. पर इस्पात राज्यमंत्री योगेंद्र मकवाना, विद्युत राज्यमंत्री सुशीला रोहतगी और खनन राज्यमंत्री रामानंद यादव का पत्ता साफ कर दिया गया. मकवाना के अलावा सभी ने राज्यसभा में महज एक कार्यकाल ही बिताया था.

इस कसौटी को भी दरकिनार कर दिया गया कि उम्मीदवार को राजीव का निजी वफादार होना चाहिए था. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी को उम्मीदवार बनाए जाने से यही जाहिर होता है. जाहिर है इसका मसकद इन दोनों दिग्गजों की ओर से असंतोष की किसी भी संभावित गतिविधि को ठंडा करना है. इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक तो पार्टी के स्थायी कोषाध्यक्ष सीताराम केसरी को बिहार से टिकट दिया जाना है. 1986 में उन्हें टिकट इस बिना पर नहीं दिया गया था कि वे राज्यसभा में अपने तीन कार्यकाल पूरे कर चुके हैं. केसरी कहते हैं, "मैं तो बस पार्टी का एक सिपाही हूं. अगर मेरे नेता राजीव गांधी ने मुझे किसी जिम्मेदारी के लिए चुना है तो मैं सचमुच उनका शुक्रगुजार हूं."

विपक्षी सरकारों वाले राज्यों में जिन इंकाइयों ने अच्छा काम किया था उन्हें भी इनाम दिया गया पर जो असरदार नहीं रहे थे उनका पत्ता कट गया. आंध्र प्रदेश के चारों इंका सदस्यों को टिकट नहीं मिला. राजीव मानते हैं उनका कामकाज अच्छा नहीं रहा था. इंका के पल्ले आंध्र से चूंकि एक ही सीट पड़ती है सो वह पार्टी के संगठन सचिव सत्यनारायण राव को दी गई. राव की काबलियत यह है कि उन्होंने मुख्यमंत्री रामराव के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जाते हुए याचिका दायर की थी.

अंतिम सूची में सबसे हैरत की बात यह थी कि इंका शासित महत्वपूर्ण राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सिफारिशें नजरअंदाज कर दी गईं. उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की सिफारिश पर किसी को भी टिकट नहीं दिया गया. पर प्रदेश इंका अध्यक्षों की बात को तरजीह दी गई. गुजरात में राज्य इंका अध्यक्ष अहमद पटेल के चहेते राजू परमार की खातिर मुख्यमंत्री अमर सिंह चौधरी के करीबी मकवाना की बलि चढ़ा दी गई. उत्तर प्रदेश के पांचों नए उम्मीदवार मुख्यमंत्री बीरबहादुर सिंह के विरोधी माने जाते हैं. इंका महासचिव वासुदेव पणिक्कर कहते हैं कि "यह सोचना गलत है कि कोई इसलिए चुना गया कि वह किसी का विरोधी है."

प्रमोद पुष्करणा

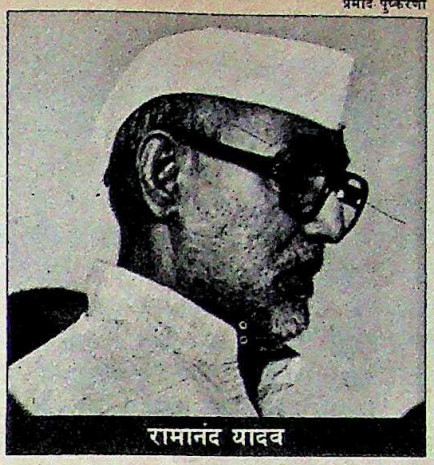

रामानंद यादव

भवान सिंह

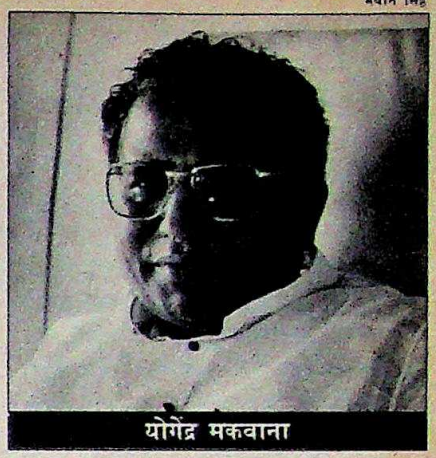

योगेंद्र मकवाना

मकवाना और यादव समेत कई केंद्रीय मंत्री फिर से टिकट पाने के लिए आलाकमान को मनाने में नाकामयाब रहे

अकेले महाराष्ट्र में ही आलाकमान ने एक को छोड़ बाकी सभी निवर्तमान सांसदों को उम्मीदवार बनाया. डी.जी. पाटील का कोई राजनैतिक 'माई-बाप' न होने से पत्ता कट गया. बाकी चारों—सुरेश कलमाडी, मुरली भंडारे, विश्वजीत सिंह बहलूवालिया और बी.एम. यादव दूसरे कार्यकाल के लिए नामजद कर दिए गए. कलमाडी ने जहां हाल ही में राजधानी में 'आजादी की दौड़' आयोजित कराई थी तो भंडारे का नाम वकीलों की हड़ताल तुड़वाने के प्रयास के कारण सुर्खियों में रहा था.

जाहिर है पार्टी में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है. शायद इसी डर से आलाकमान वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों को प्रमुख राज्यों में भेज रहा है. इनका काम यह सुनिश्चित करना है कि मतदान के समय असंतुष्ट लोग पाला न बदल लें.

इंका की इस चिंता की वजहें भी हैं. आखिर पार्टी राज्यसभा की 10 सीटें खो बैठी है, अब 242 सदस्यीय सदन में उसका दो तिहाई बहुमत नहीं रह जाएगा. उधर विपक्ष की ताकत में इजाफा हुआ है. मसलन जनता पार्टी को छह सीटों का फायदा हुआ है. तेलुगु देशम की भी ताकत बढ़ी है. लोकदल (ब) और भाजपा की दो-दो सीटें बढ़ जाएंगी. लोकदल (अ) को जनता पार्टी से विलय का फायदा मिलेगा, इस चक्कर में उसने सुब्रह्मण्यम स्वामी राज्यसभा में पहुंच जाएंगे. वे उत्तर प्रदेश से खड़े चार विपक्षी उम्मीदवारों में एक हैं. लेकिन जनता पार्टी के लिए एक छोटी-सी समस्या है जो मशहूर वकील राम जेठमलानी की कर्नाटक से नामजदगी के कारण पैदा हुई है. वे बंबई के रहने वाले हैं पर पर्चा भरने के लिए उन्होंने बंगलूर की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराया है. वे चूंकि जनता पार्टी के सदस्य नहीं हैं इसलिए सैय्यद शहाबुद्दीन समेत पार्टी के कई लोगों ने उन्हें समर्थन देने के मुख्यमंत्री हेगड़े के फैसले का विरोध किया है. शहाबुद्दीन तो जनता संसदीय बोर्ड से इस्तीफा देने की हद तक चले गए. मगर हेगड़े ने यह दलील दी है कि वे कारगर सांसद साबित होंगे. उनकी बात में दम भी है. जेठमलानी के राज्यसभा में आने की खबर से इंका खेमे में दहशत फैल गई है क्योंकि पार्टी के लोग उनके तीखे हमलों से खौफ खाते हैं. यही वजह है कि केंद्रीय गृहमंत्री कुछ दिन तक इसी उम्मीद में बंगलूर में डेरा डाले थे कि वे जेठमलानी के खिलाफ मतदान के लिए जनता विधायकों से पाला बदलवाने में सफल हो जाएंगे.

कुछ भी हो, अब राज्यसभा में विपक्ष का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा. और विपक्ष के धुरंधरों की मौजूदगी इंका को परेशान किए रहेगी. शायद इसलिए राजीव को यह एहसास हुआ होगा कि पार्टी के लोगों को ज्यादा समय तक नाराज रखना ठीक नहीं. इंका महासचिव गुलाम नबी आजाद ने आलाकमान के ताजा सोच को बखूबी अभिव्यक्त किया है, "जिन्हें टिकट नहीं मिला वे अच्छे लोग हैं. पर जिन्हें मिल गया वे भी अच्छे हैं." लगता है इंका नेताओं को यह प्रसिद्ध राजनैतिक पाठ बखूबी समझ में आ गया है कि पार्टी में हर किसी को हमेशा खुश नहीं रखा जा सकता.

—प्रभु चावला

प्रशांत पंजियार

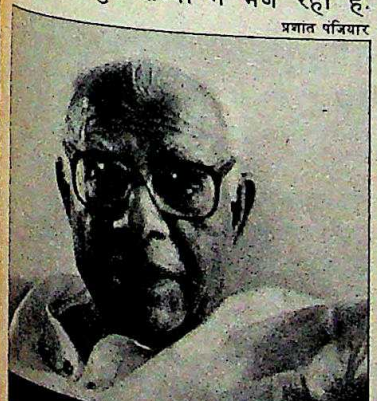

राम जेठमलानी

श्याम टेकवानी

सुब्रह्मण्यम स्वामी

हालांकि जेठमलानी और स्वामी को जनता पार्टी का टिकट तो मिल गया, लेकिन इससे पार्टी में बवाल खड़ा हो गया

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इंडियन एक्सप्रेस

नहले पर दहला

कमलनाथ चुनौती की मुद्रा में

इससे अच्छी भिड़ंत और क्या हो सकती है. एक जेहादी पत्रकार है तो दूसरा धांसू नेता. लिहाजा पिछले पखवाड़े जब 'इंडियन एक्सप्रेस' के संपादक अरुण शौरी और मध्य प्रदेश से चुनकर आए सांसद कमलनाथ एक दूसरे से भिड़े तो चिंगारी दूर तक फैल गई. झगड़ा कमलनाथ के बारे में किए गए एक भंडाफोड़ से हुआ और यह भंडाफोड़ किया था अरुण शौरी ने.

शौरी ने जब 'एक सांसद और दो खाते' शीर्षक से कमलनाथ के बारे में यह खबर लिखी तो सोचा कि इस कांग्रेस(इ) सांसद की गरदन अब उनकी मुट्ठी में है. खबर में उनकी कंपनी के विदेशी खातों का जिक्र था जिसे शौरी ने गैरकानूनी बताया था.

खबर के मुताबिक ईएमसी स्टीलाल लिमिटेड का, जिसे कमलनाथ का परिवार चलाता है, दुबई में दो करोड़ रुपए और रियाद में 3 करोड़ रुपए का खाता है. कमलनाथ इस कंपनी में निदेशक हैं. इस खबर ने संसद में तूफान खड़ा कर दिया और विपक्ष के नेता मधु दंडवते ने खातों की जांच की मांग की. पर कमलनाथ ने भी पलट कर प्रहार करने की ठान ली.

कमलनाथ ने एक अनोखा प्रस्ताव रखा कि इस मामले की जांच के लिए एक समिति बनाई जाए और उसके सदस्यों का चुनाव विपक्ष ही करे. यह शौरी के लिए एक चुनौती थी. शौरी ने दूसरे दिन एक और खबर लिखी कि कमलनाथ ने इन विदेशी खातों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की इजाजत नहीं ली थी. शौरी ने संसद से अनुरोध किया कि "उसे कमलनाथ की बात मान लेनी चाहिए."

लेकिन कमलनाथ के बारे में पार्टी आलाकमान के मन जो भी संदेह थे, वे अब तक खत्म हो चुके थे. उन्होंने असरदार ढंग से अपना पक्ष रखा और अपनी पार्टी को यह भरोसा देने में कामयाब हो गए कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है. यह बात उस समय बिलकुल साफ हो गई जब एन.जी. रंगा और सत्येंद्रनारायण सिन्हा जैसे वरिष्ठ पार्टी नेताओं ने उनका समर्थन किया और आरोपों की जांच के लिए विशेषाधिकार समिति बनाने का प्रस्ताव पेश किया.

कमलनाथ कहते हैं, "दुर्भाग्य की बात है कि शौरी सिर्फ दो ही खातों का पता लगा पाए. असल में हमारे पास ऐसे 22 खाते हैं और वे सब कानूनी हैं." स्टीलाल का मुख्य व्यवसाय मध्य पूर्व के देशों में संचार लाइन टावर खड़े करने और उनकी देखरेख से संबंधित परियोजनाएं चलाना है. कंपनी के रिकार्ड के मुताबिक, कलकत्ता स्थित रिजर्व बैंक के विनिमय नियंत्रण विभाग ने उसे विदेशों में खाते खोलने की इजाजत 1980 से दी हुई है.

'इंडियन एक्सप्रेस' के वित्तीय सलाहकार एस. गुरुमूर्ति और खुद रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक इसके लिए रिजर्व बैंक के बंबई कार्यालय से इजाजत ली जानी चाहिए थी न कि कलकत्ता कार्यालय से. पर कमलनाथ अपनी बात पर अडिग हैं कि उन्होंने खाता खोलने के लिए उपयुक्त अधिकारियों से अग्रिम इजाजत ले ली थी.

लगता है शौरी को ये सूचनाएं संसदीय प्रवर्तन निदेशालय की जांच से मिलीं थी. शौरी का प्रमुख सबूत बंबई के रिजर्व बैंक की वह चिट्ठी है जो 1981 में प्रवर्तन निदेशालय को लिखी गई थी. इसमें कहा गया था कि "हमें नहीं लगता कि हमने कंपनी को विदेशी खाता खोलने की इजाजत दी है." प्रवर्तन निदेशालय की जांच के बाद 31 मई 1985 को कमलनाथ के कलकत्ता कार्यालय और दिल्ली निवास पर छापा मारने की योजना भी बनाई गई थी. शौरी की खबर के लिए शोध करने वाले गुरुमूर्ति का कहना है कि ऊपर से राजनैतिक दबाव पड़ने की वजह से छापों का आदेश वापस ले लिया गया. पर कमलनाथ कहते हैं कि आदेश इसलिए वापस लिया गया कि वे राजस्व विभाग को यह समझाने में कामयाब रहे कि उन्होंने जरूरी इजाजत ले ली थी और रिजर्व बैंक व प्रवर्तन निदेशालय के बीच का पत्राचार भ्रामक है.

यह सब उस समय हुआ जब विश्वनाथ प्रताप सिंह वित्तमंत्री, विनोद पांडे राजस्व सचिव और भूरे लाल प्रवर्तन निदेशक थे. इस तिकड़ी के बारे में माना जाता था कि यह किसी के सामने आसानी से नहीं झुकती थी. इसलिए अगर छापो का आदेश वापस लिया गया तो इसका यही मतलब निकलता है कि कमलनाथ का पक्ष मजबूत था.

लेकिन 'इंडियन एक्सप्रेस' के सूत्र लगातार दावा कर रहे हैं कि उनके पास और भी दस्तावेज हैं जिन्हें वे विशेषाधिकार समिति के सामने पेश करेंगे. अब यह फैसला संसद को करना है कि कौन ज्यादा भरोसेमंद है—शौरी या कमलनाथ. और यदि इंका सांसद शौरी को मात देने में सफल हो गए तो अप्रत्यक्ष रूप से राजीव गांधी का ही फायदा होगा जिसे वे शायद ही भूलें.

—कमलजीत रवल

कार्टून अजीत नारकर

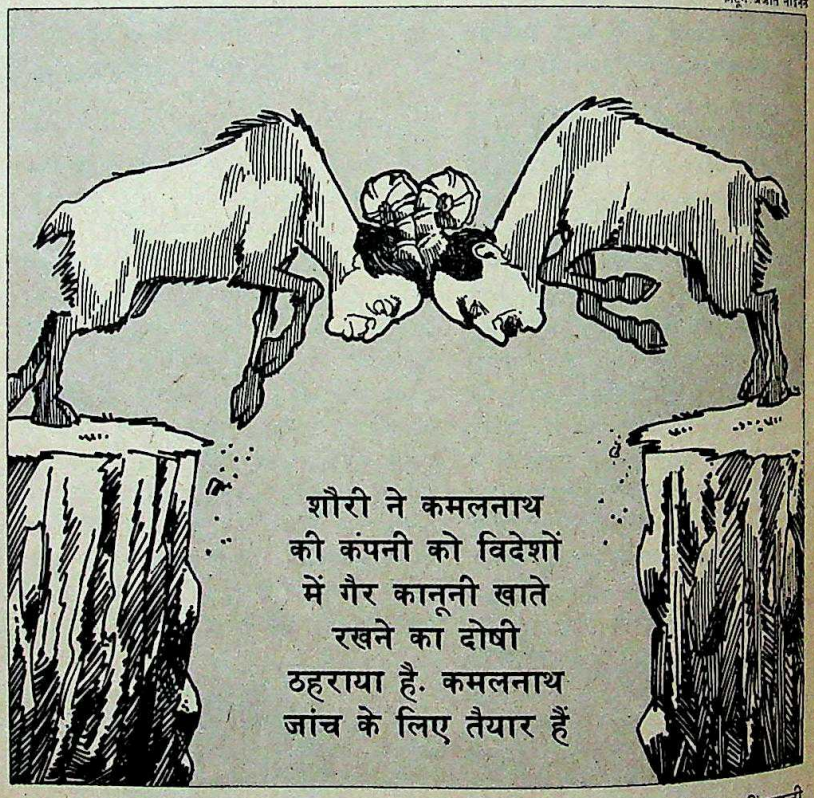

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

चड्ढा प्रकरण

उलझी गुत्थी में नया पेंच

विन चड्ढा की वापसी ही मामले की असल कुंजी

फासत से सूट पहने, नीली कमीज पर लाल टाई लगाए, आंखों पर चश्मा चढ़ाए वह युवक पिछले पखवाड़े लुफ्तहंसा की एलएच-760 उड़ान से जब पालम हवाई अड्डे पर उतरा तो यूरोप से लौट रहे दूसरे अमीर व्यापारियों की तरह ही लग रहा था. पूरे आत्मविश्वास से टहलता हुआ वह सीमा शुल्क काउंटर की ओर बढ़ा.

पर उसे पता नहीं था कि पासपोर्ट में लिखे उसके नाम—हर्ष चड्ढा को पढ़ते ही आव्रजन काउंटर के कंप्यूटर हरकत में आ गए हैं. उसका नाम उन लोगों की फेहरिस्त में था जिनके खिलाफ 'लुक आउट काल' (एलओसी) यानी तलाश करने का आदेश जारी हुआ है. कंप्यूटर पर एलओसी चेतावनी के संकेत चमके तो अलसाया-सा आव्रजन अधिकारी एक झटके में जाग उठा. और उसने प्रवर्तन विभाग के जासूसों को तुरंत फोन कर दिया.

प्रवर्तन विभाग के वरिष्ठ अफसरों का एक अमला विशेष निदेशक की अगुआई में तुरंत हवाई अड्डे जा पहुंचा. वहां सीमा शुल्क अधिकारी चड्ढा के सामान का निबटारा करने में जानबूझकर देरी कर रहे थे. शिनाख्त के बाद अफसर उस युवक को पूछताछ के लिए मुख्यालय ले आए. और इस तरह बोफोर्स की उलझी हुई पहेली का एक और पेचीदा अध्याय शुरू हो गया. इस पहेली को सिर्फ एक ही आदमी बूझ सकता है, वह है इस युवक का पिता विशेश्वरनाथ चड्ढा जो 'विन चड्ढा' के नाम से मशहूर हैं. 62 वर्षीय चड्ढा और उसका 31 वर्षीय दत्तक पुत्र हर्ष, पिछली मई में देश छोड़कर अमेरिका चले गए थे. तब से वे वहीं हैं.

पर पिछले पखवाड़े हर्ष की अचानक वापसी से चकरा देने वाले कई सवाल उठ खड़े हुए हैं. यह जानते हुए भी वह क्यों लौटा कि पूछताछ के लिए उसे धर लिया जाएगा? क्या सरकार को मालूम था कि वह लौट रहा है? अगर हां, तो क्या हवाई अड्डे पर जो कुछ भी हुआ वह क्या लोगों को सिर्फ यही दिखाने के लिए था कि चड्ढा का मामला अभी ठंडे बस्ते में नहीं गया है? सवालों की गंभीरता तब और भी बढ़ गई जब भारत में बोफोर्स की प्रशासनिक सलाहकार एनाट्रॉनिक्स जनरल कार्पोरेशन के इस सह-निदेशक को 18 घंटे की पूछताछ के बाद ही छोड़ दिया गया. बाद में वह दिल्ली की एक अदालत से जमानत का आदेश लेकर चहलकदमी करता हुआ बाहर निकला. प्रवर्तन निदेशालय ने जमानत का विरोध तक नहीं किया. बाद में हर्ष ने अपने दोस्तों से कहा, "मैं घर वापस आना चाहता था और आ गया."

न तो प्रवर्तन निदेशालय ने और न ही सीबीआई ने यह जांच की कि चड्ढा अमेरिका में किस हैसियत से रह रहा है

बेटे की वापसी के तीन दिन बाद अमेरिकी सरकार ने घोषणा की कि विन चड्ढा के पास ग्रीन कार्ड नहीं है. भारत के अमेरिकी दूतावास ने भी इसकी पुष्टि कर दी जबकि पहले यही माना जाता था कि चड्ढा के पास ग्रीन कार्ड है. इस चौंका देने वाली खबर ने मामले को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया. विन चड्ढा का पासपोर्ट भारत सरकार रद्द कर चुकी है. इस नाते अमेरिका में उसका रहना गैर-कानूनी है.

अमेरिकी अधिकारियों ने ही सबसे पहले कहा था कि चड्ढा के पास ग्रीन कार्ड है. पर पिछले पखवाड़े उन्होंने बयान पलट दिया. 'इंडिया टुडे' के अनुरोध पर अमेरिकी इमिग्रेशन ऐंड नेचुरलाइजेशन सर्विस ने विशेश्वरनाथ चड्ढा का नाम पता करने के लिए अपने कंप्यूटरों को छान मारा. कंप्यूटरों के मुताबिक इस आदमी को अमेरिका में "नवंबर 1967 में स्थायी नागरिक के तौर पर प्रवेश दिया गया था." दूसरे शब्दों में, अमेरिकी आव्रजन विभाग के दस्तावेजों के अनुसार चड्ढा के पास ग्रीन कार्ड है (या था).

विन चड्ढा; और हर्ष (बाएं) अदालत में अपने वकील के साथः रहस्य बरकरार

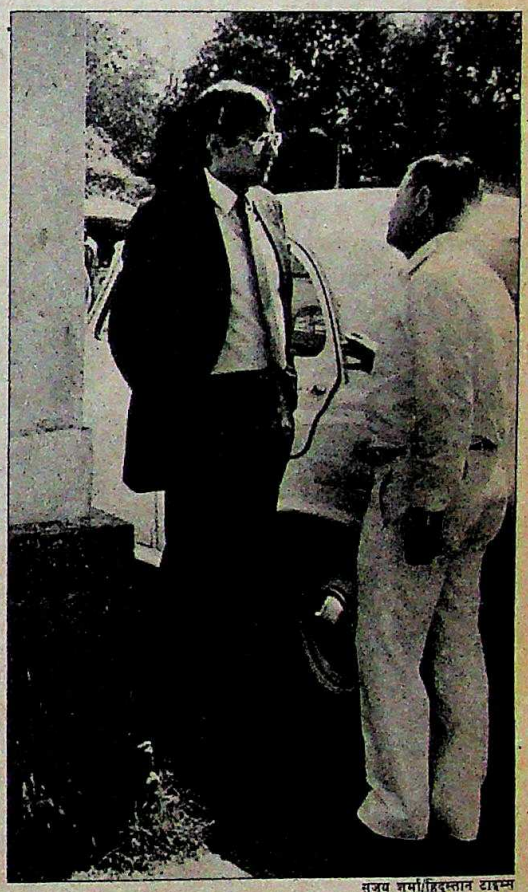

संजय शर्मा/हिंदुस्तान टाइम्स

यह गुत्थी सुलझ तभी सकती है जब पता लगे कि भारत सरकार विन चड्ढा को वापस लाने के प्रति कितनी गंभीर है. प्रवर्तन निदेशक अनिल कुमार जोर देकर कहते हैं, "हमें अभी भी उसकी जरूरत है." पर शुरू से ही विभिन्न सरकारी विभाग इस मामले से जिस तरह निबट रहे हैं उससे संदेह तो बना ही हुआ है. पिछली जनवरी में कुमार विन चड्ढा से पूछताछ के लिए अमेरिका चले तो गए पर उनके रवाना होने से पहले

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रवर्तन निदेशालय ने नई दिल्ली के अमेरिकी दूतावास से यह तक पता लगाने की जहमत नहीं उठाई कि विन चड्ढा किस हैसियत से अमेरिका में रह रहा है. इस बात का पता न तो सीबीआई ने लगाया और न बोफोर्स सौदे की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति की जांच एजेंसी ने. चड्ढा के प्रत्यावर्तन का मसला भी विदेश मंत्रालय आठ महीने से दाबे बैठा है.

और दो जांच एजेंसियां लगी होने के बावजूद लगता है सरकार अब तक चड्ढा से सिर्फ अपने मतलब की बात ही उगलवा पाई है. यानी बोफोर्स सौदा हासिल करने के लिए रिश्वत देने के आरोप से मुक्ति.

इन्हीं वजहों से यह लगने लगा कि सरकार असल में मामले को आगे बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है. चड्ढा के खिलाफ फिलहाल मामला यह है कि उसने पूछताछ के लिए भेजे गए प्रवर्तन अधिकारियों के समन की तामील नहीं की.

हर्ष चड्ढा की जमानत याचिका का निदेशालय ने इस आधार पर कोई विरोध नहीं किया कि वह 'कुछ नहीं जानता.' बाप-बेटे ने जो कुछ भी कबूला उसका मिलान भारत में मौजूद बोफोर्स के तकनीकी कर्मचारियों तक से नहीं किया गया. बोफोर्स की ओर से 4 लाख रुपए मुआवजे का भुगतान करने के एक अपेक्षाकृत हल्के आरोप के सिलसिले में एनाट्रॉनिक्स को कोई कारण बताओ नोटिस भी जारी नहीं किया गया.

स्विस बैंक के जरिये बोफोर्स ने 64 करोड़ रुपए का भुगतान किसे किया? प्रवर्तन निदेशलय इस अहम आरोप की परछाई भी नहीं पा सका है. स्वीडिश ऑडिट ब्यूरो की रिपोर्ट सिर्फ इतना ही कहती है कि निपटान (वाइंडिंग अप चार्जेस) का भुगतान 'दूसरों के साथ-साथ भारत में बोफोर्स के एजेंट' को भी किया गया. चड्ढा इस बात से इनकार करता है कि वह बोफोर्स का एजेंट था. उसका कहना है कि वह तो सिर्फ प्रणासनिक सलाहकार था. उसके बदले हर महीने बाकायदा भारतीय रिजर्व बैंक के मार्फत उसे 100,000 क्रोनर (तकरीबन दो लाख रुपए) मिल जाया करते थे.

उसके पारिवारिक दोस्तों के मुताबिक विन चड्ढा सफर करने लायक होते ही वापस लौट आना चाहता है. पर चड्ढा की वापसी से बोफोर्स मामला फिर तूल पकड़ेगा जिससे सरकार बचना चाहती है. लेकिन यह भी निश्चित है कि उसके यहां आने से ही कई सवालों के जवाब मिल सकेंगे.

—**पंकज पचौरी** और ब्यूरो रिपोर्ट

पश्चिम बंगाल

हिंसा का जुनून

40 दिन के बंद में उपद्रव

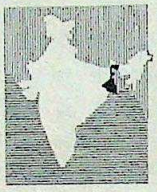

सब कुछ हो जाने पर आंदोलनकारियों का अपने फायदे-नुकसान पर विचार करना स्वाभाविक ही है. 20 मार्च को खत्म हुए 40 दिन के बंद के दौरान दार्जिलिंग ने हत्या और तोड़फोड़ के कई रूप देखे. बंद की अपील गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा (जीएनएलएफ) ने पुलिस और सीआरपी के 'जुल्मों' के विरोध में की थी. बंद खत्म होने तक छह जवानों समेत 60 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा और जीएनएलएफ के दूसरी पांत के तकरीबन 450 कार्यकर्ता आतंकवाद विरोधी कानून के तहत जेल में बंद कर दिए गए. लेकिन मोर्चे के बड़े नेता या तो भूमिगत हो गए या सीमा लांघ कर सिक्किम और नेपाल चले गए. कुल 1,200 लोग गिरफ्तार हुए. 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया.

लेकिन आंदोलनकारी पुलिस और सीआरपी के दमनचक्र से बिलकुल भयभीत नहीं हुए. कलिम्पोंग सबडिवीजन में उन्होंने पानी और बिजली की लाइनें काट दी जिससे वहां जनजीवन एक पखवाड़े तक अस्त-व्यस्त रहा. कलिम्पोंग की तकरीबन सारी सरकारी इमारतों और सामरिक महत्व के पुल उड़ा दिए गए.

उग्रवादियों ने कलिम्पोंग के कई इलाकों को 'आजाद इलाका' घोषित कर दिया. पुलिस उप-महानिरीक्षक रोमेश कुमार हांडा बताते हैं कि इनमें से एक "क्षेत्र की तो अपनी ही अदालतें, मजिस्ट्रेट और यहां तक कि एक जेल भी थी." पर अंततः पुलिस ने उग्रवादियों का यह खेल खत्म कर दिया.

लेकिन जैसे-जैसे हिंसा की लपटें दूसरी जगहों पर फैलती गई घीसिंग की गिरफ्तारी की मांग भी जोर पकड़ती गई. हांडा कहते हैं, "घीसिंग को उन सीधे-सादे लोगों से ही समर्थन मिलता है जो यह मानते हैं कि घीसिंग कानून से ऊपर हैं. अगर उन्हें जेल में डाला दिया गया तो लोगों को उनकी औकात का पता चल जाएगा."

हालांकि, यह तो राजनैतिक फैसले पर निर्भर करेगा. लेकिन पुलिस वाले ठोस कारण बताते हुए कड़े कदम उठाने की वकालत करते हैं. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रंजीत पचनंदा ने एक छापे के दौरान दो किस्म की पांच तोपें, तीन इंच व दो इंच के गोले, काफी तादाद में जिलेटिन की छड़ें, डाइनामाइट, इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया से दगने वाली सुरंगे और अति-विस्फोटक हथगोले बरामद किए.

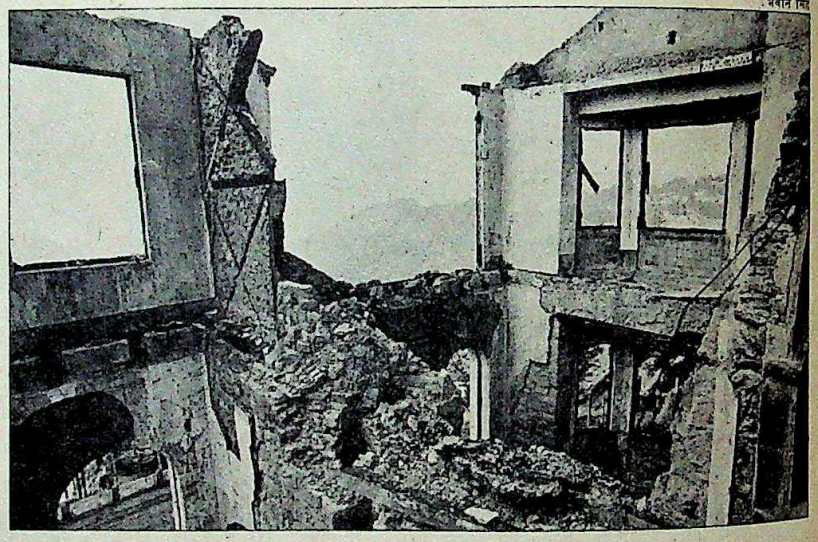

भवान चिब

उग्रवादियों द्वारा ध्वस्त इमारत

लगता है कि मुख्यमंत्री ज्योति बसु दार्जिलिंग में पर्वतीय विकास परिषद के लिए विधानसभा में प्रस्तावित विधेयक पेश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. घीसिंग के एतराजों को नजरअंदाज करते हुए वे कहते हैं, "घीसिंग मानें या न मानें, हमें जो करना है करेंगे." लेकिन बसु का इतना उतावलापन खतरनाक भी हो सकता है क्योंकि इन सुलगती पहाड़ियों पर घीसिंग का दबदबा कायम है.

—**कमलजीत रतन**, दार्जिलिंग से

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

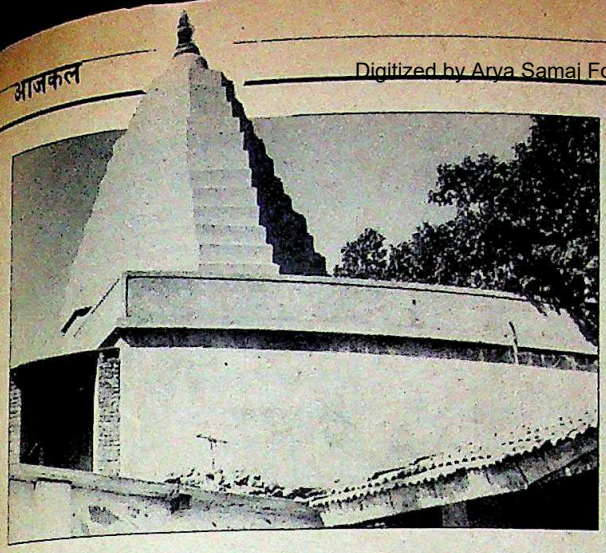

गेरविन क्रास्ट/इंडियन पोस्ट

आदिमाता मंदिर (एकदम बाएं), शिंदे परिवार (ऊपर) और नंदिनी

ठाणे

मासूम की नामालूम मौत

नंदिनी की हत्या हुई या बलि दी गई

ठाणे के बाहरी इलाके में स्थित शांत-सी बस्ती— चितलसर-मानपाड़ा में गुपचुप फैलती अफवाहें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं: पिछले 15 वर्षों से हर 19 मार्च— महाराष्ट्रीय हिंदुओं के नववर्ष— 'गुड़ी पाडवा' को कोई न कोई व्यक्ति यहां से रहस्यमय ढंग से गायब हो जाता है.

इस कहानी की सचाई संदेहास्पद है पर 19 मार्च को 7 साल की एक बच्ची नंदिनी चंद्रकांत शिंदे की रहस्यमय हत्या और इस सिलसिले में पड़ोस के मंदिर के पुजारी की गिरफ्तारी से इन अफवाहों का एक वीभत्स रूप सामने आया है. उस शाम नंदिनी अपने मां-बाप से यही कहकर घर से बाहर निकली थी कि वह मंदिर जा रही है.

उस शाम ज्योंही आदिमाता शक्ति मंदिर में आरती की घंटियां बजनी शुरू हुईं, नंदिनी अपना खाना अधूरा ही छोड़कर मंदिर की ओर दौड़ पड़ी. मंदिर नंदिनी के घर से महज 50 गज दूर है. नंदिनी एक बार जो गई तो दोबारा नहीं लौटी.

जब नंदिनी रात दस बजे तक भी घर नहीं पहुंची तो उसके पिता चंद्रकांत शिंदे ने कपूरवाड़ी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाई. तीन दिन बाद शिंदे के पड़ोसी दत्तात्रय कामठेकर द्वारा व्यक्त किए गए संदेह के आधार पर पुलिस ने मंदिर के साथ बनी गौशाला की तलाशी ली. पुलिस ने वहां उपलों के ढेर में दबा बच्ची का विकृत शव बरामद किया. पुलिस ने मंदिर के पुजारी नारायण अंगारा पुजारी और दो दूसरे लोगों को गिरफ्तार कर लिया.

चितलसर-मानपाड़ा के निवासियों को पक्का यकीन है कि यह नरबलि का ही मामला है. स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर में खून से सने एक डम के पास एक नींबू और सिंदूर भी पड़ा मिला था. मंदिर परिसर की तलाशी के दौरान मौजूद क्षीरसागर का कहना है कि "बच्ची के दाएं हाथ की छोटी उंगली में कटे का निशान भी था." यह तांत्रिकों द्वारा चैत्र पर्व नवरात्रि को बलि चढ़ाने के अनुष्ठान का एक हिस्सा होता है. लेकिन कपूरवाडी के पुलिस इंस्पेक्टर आर.एम. पाटील, जिनकी उपस्थिति में शव ढूंढ़ा गया था, इसे मानने से इनकार करते हैं. पुलिस ने अब तक इसे वीभत्स नरबलि का मामला नहीं माना है.

ठाणे के पुलिस आयुक्त मोहन वाधवा कहते हैं, "हमें अभी तक इस बात का कोई सबूत नहीं मिल पाया है कि यह नरबलि का मामला है. अभी तक जो संकेत मिले हैं, उनसे यह बलात्कार और हत्या का मामला नजर आता है."

लेकिन यहां के निवासियों को अब भी पूरा विश्वास है कि नंदिनी की बलि दी गई. सुवर्णा परब, जो कि शव की बरामदी के वक्त वहां मौजूद थीं, कहती हैं, "उसके कपड़े बिलकुल सही-सलामत थे. माथे पर थोड़े से जख्मों के अलावा उसके शरीर पर किसी किस्म की चोट के चिन्ह नहीं थे." लेकिन एक पुलिस अधिकारी इसका स्पष्टीकरण देते हैं कि विकृत मनोवृत्ति के लोग ऐसे ही निरीह लोगों को अपना शिकार बनाना पसंद करते हैं, जो किसी प्रकार का प्रतिवाद न कर पाएं.

इस सनसनीखेज मामले से पुजारी संदेह के घेरे में आ गया है. उसका पूर्व इतिहास भी संदिग्ध रहा है. यह पुजारी मूलतः मंगलूर का रहने वाला है और खुद को नित्यानंद का अनुयायी बताता है. उसके अनुयायियों में युवा महिलाओं की बड़ी तादाद है. इनमें अधिकांश बंबई, पुणे और मैसूर की हैं.

वाधवा कहते हैं. "यह पुजारी पहले ठाणे के कोलीवाड़ा में रहता था. वहां वह महिलाओं के साथ संबंधों को लेकर काफी बदनाम हो चुका था. उसे वहां से निकाल दिया गया. उसके अपने सहयोगी गंगाधर शेट्टी (उसे भी गिरफ्तार किया गया है) की पत्नी के साथ अवैध संबंध थे." पुलिस उपायुक्त हेमंत करकरे कहते हैं, "हम तो चाहते हैं कि पुजारी का पर्दाफाश करें लेकिन इसके पर्याप्त सबूत नहीं मिल रहे और हत्या का उद्देश्य पता नहीं चल रहा."

लेकिन बस्ती के निवासी अब भी अपना दावा दोहराए जा रहे हैं कि पिछले 15 वर्ष से यहां से हर साल 19 मार्च को एक व्यक्ति गायब हो जाता है. लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाई क्योंकि अभी तक ऐसा एक भी मामला पुलिस में दर्ज नहीं किया गया. लेकिन ठाणे के उपमहापौर बालचंद्र तांगड़ी कहते हैं, " आठ साल पहले मेरा भतीजा भी इसी समय लापता हो गया था. उसका शव एक कुएं से बरामद हुआ. लेकिन हमने रिपोर्ट नहीं लिखवाई."

नंदिनी की वीभत्स हत्या के संदर्भ में पुलिस के लिए नरबलि वाले मामले से निबटने के बजाय बलात्कार और हत्या के मामले को सुलझाना ज्यादा आसान है. क्योंकि नरबलि का मामला निकलने की स्थिति में पुलिस की काफी किरकिरी होगी.

—**सलिल त्रिपाठी**, चितलसर-मानपाड़ा में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पंजाब

करनी और कथनी का फर्क

इमरजेंसी विधेयक का औचित्य आम जनता की समझ से परे

पिछले पखवाड़े पंजाब की लड़ाई उस राज्य की खूंरेज युद्धभूमि पर तो तेज हुई ही, नई दिल्ली में एक नए आयाम में दाखिल हो गई. वहां हर रोज दस से ज्यादा हत्याएं (1987 के औसत के मुकाबले तिगुनी) जारी रहते हुए भी, केंद्र ने तेजी से गिरती अपनी साख बचाने की कोशिश की. भारी विरोध के बावजूद उसने संसद के दोनों सदनों में 59वां संविधान संशोधन विधेयक पारित करवा लिया. इससे उसे राज्य की अंदरूनी गड़बड़ी पर काबू पाने के लिए इमरजेंसी लागू करने का अधिकार मिल गया है.

उग्रवादियों ने खतरनाक धमाका करके तुरंत इसका जवाब दिया. उन्होंने रूस में बने एक रॉकेट प्रक्षेपक (आरपीजी) से 2.25 किलोग्राम वजन का 85 मिमी का गोला फगवाड़ा के करीब विश्वकर्मा मंदिर पर फेंका. वहां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के 63 जवान तैनात थे. सौभाग्य से वे बाल-बाल बच गए क्योंकि गोला 13 इंच मोटी दीवार को भेदता हुआ पक्की सीढ़ियों से जा टकराया. एक मच्छरदानी जल जाने के सिवा नुकसान तो कोई खास नहीं हुआ पर इसमें निहित संदेश खतरनाक था. और यह कि आतंकवाद अब बड़ी बगावत के करीब पहुंच गया है. 99 सेंमी लंबा आरपीजी-7 वी दुनिया भर में गुरिल्लाओं का मानक हथियार है. इस बेहद कारगर मारक हथियार का मजा भारतीय सेना भी जाफना में चख चुकी है.

दरअसल सिख आतंकवादियों ने आरपीजी का इस्तेमाल पहली बार नहीं किया है. ऑपरेशन ब्लूस्टार के दौरान ऐसे दो प्रक्षेपक वे इस्तेमाल कर चुके हैं. इस साल भी उन्होंने अमृतसर जिले के कत्थूनंगल और मजीठा में सीआरपीएफ की गश्ती टुकड़ियों पर आरपीजी से नाकाम हमले किए थे.

लेकिन पिछले पखवाड़े के हमले में फर्क था. पहली बार उन्होंने काफी सोच-विचार के बाद आरपीजी का इस्तेमाल किया था. केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक अधिकारी कहते हैं, "यह घात लगाकर किए गए आम हमले से अलग किस्म की घटना थी. उन्होंने इसकी मुकम्मल योजना बनाई, मोर्चेबंदी की और फिर सीआरपीएफ के मजबूत अड्डे पर हमला किया. यह आने वाले खतरे का ही संकेत है."

हालांकि इस हमले ने पुलिस को जोरदार झटका दिया, पर इसके लिए चुना गया वक्त केंद्र के लिए राजनैतिक तौर पर उपयुक्त था. तब केंद्र सरकार विपक्ष के कड़े विरोध के बावजूद संसद में विवादास्पद इमरजेंसी विधेयक पारित कराने की परेशानियों से जूझ रही थी. विधेयक पेश करते हुए केंद्रीय गृहमंत्री बूटा सिंह ने कहा कि पंजाब में आतंकवाद उस हद तक पहुंच गया है, जहां सरकार को असामान्य अधिकारों की जरूरत है. लेकिन विपक्ष का मानना था कि यह विधेयक परोक्ष रूप से इमरजेंसी का रास्ता खोल देगा. जनता पार्टी के मधु दंडवते ने कहा, "यह विधेयक गैरकानूनी और अनैतिक है तथा आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर इमरजेंसी घोषित करने के खिलाफ राष्ट्रीय जनमत का उल्लंघन करता है."

लेकिन सरकार का कहना है कि पंजाब की स्थिति को देखते हुए उसके सामने विधेयक लाने के सिवा कोई चारा न था. फिर भी अधिकारी यह नहीं बता पाते कि इमर-

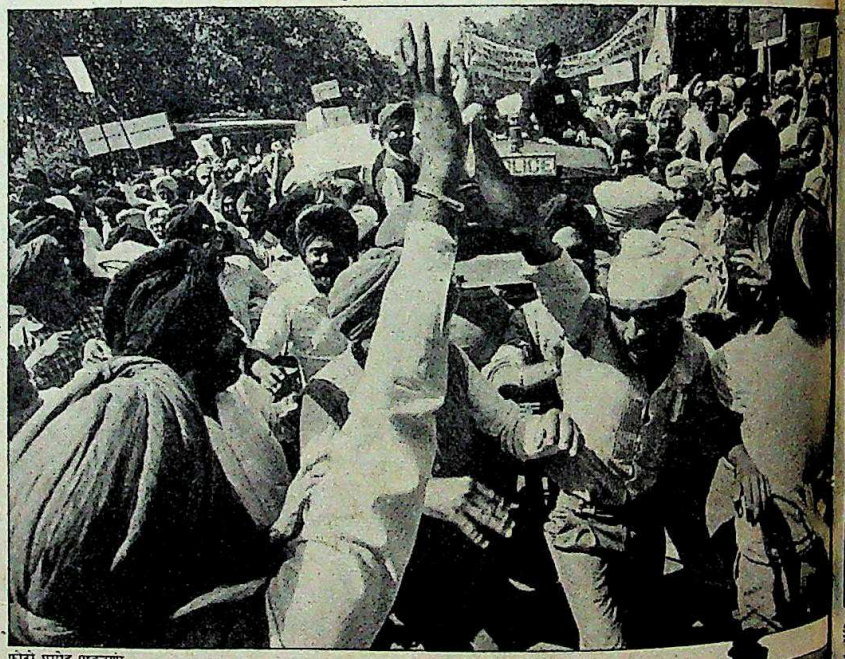

फोटो: प्रमोद पुष्करणा

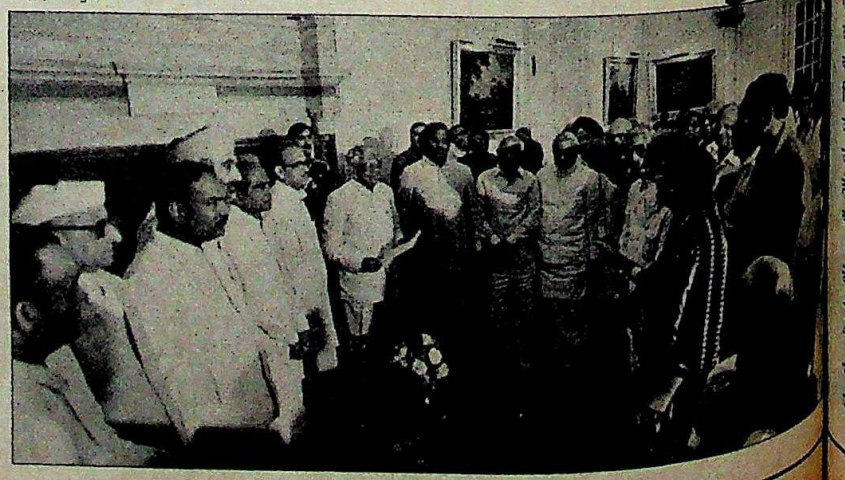

इमरजेंसी विधेयक का विरोध करते सिख (ऊपर); इसके खिलाफ विपक्षी नेताओं का राष्ट्रपति को ज्ञापन: खतरनाक कदम

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वैसी विधेयक समस्या से निबटने में किस प्रकार मददगार होगा. पंजाब के लिए विशेष रूप में बनाए गए 18 बड़े कानूनों के रहते सरकार के पास वैसे भी इमरजेंसी जितने अधिकार हैं. (देखें 'कसौटी').

सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता भी इस संबंध में पाकिस्तान में रचे जा रहे नए षड्यंत्रों का हवाला देते हैं, जिनसे 'युद्ध स्तर पर निबटने' की जरूरत है. कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री दरबारा सिंह कहते हैं, "पाकिस्तान और दूसरी विदेशी ताकतों के लिए पंजाब भारत पर हमला करने का बेहतरीन रास्ता है." इसलिए उनका तर्क था कि न केवल 'अंदरूनी, बल्कि बाहरी खतरों से निबटने के लिए भी' पंजाब में इमरजेंसी अधिकारों की जरूरत है.

विपक्ष को इस विधेयक में जहां इंदिरा गांधी की इमरजेंसी की काली छाया दीखती है, वहीं पंजाब में गैर-इंका नेताओं की भी यही तीखी प्रतिक्रिया थी. एकीकृत अकाली दल के सांसद भाई शमिंदर सिंह का कहना था, "यह एक और क्रूर प्रयोग है. जिस हिसाब से इंका संविधान में संशोधन करती जा रही है, उससे लगता है कि हमारे सामने जल्दी ही 21वीं सदी का वह संविधान होगा जिसका देश के मूल संविधान से दूर का भी वास्ता नहीं रहेगा."

यहां तक कि अकाली दल (लोंगोवाल) के बलवंत सिंह रामूवालिया सरीखे जाने-माने उदारपंथी भी इस कदम से बेहद खिन्न हैं. "पहले उन्होंने लोंगोवाल, बरनाला और राजी की मिट्टी पलीद की तथा अब भाई जसबीर सिंह और जैन मुनि सुशील कुमार की हैसियत भी खतरे में पड़ गई है. सरकार कितनी बेईमान है." उन्होंने चेतावनी दी है कि इमरजेंसी से आतंकवादियों की स्थिति तर्कसंगत बनेगी. "इससे उनके इस आरोप को ही बल मिलेगा कि पंजाब के लिए एक किस्म के कानून हैं और बाकी देश के लिए दूसरे."

दूसरे आकाली नेताओं की तरह रामूवालिया और शमिंदर सिंह का भी आरोप है कि यह विधेयक पंजाब में गड़बड़ी बनाए रखने और दूसरे राज्यों में चुनावी फायदा बटोरने के हथकंडे से ज्यादा कुछ नहीं है. पंजाब के पूर्व कृषिमंत्री अमरिंदर सिंह का आरोप है, "वे पंजाब में हालात इस हद तक बिगाड़ देंगे कि उससे निबटने के लिए राजीव को कोई 'चमत्कार' दिखाना पड़े. तभी वे मध्यावधि चुनाव कराएंगे." पर केंद्र ने इसका जोरदार खंडन किया है. दरबारा सिंह कहते हैं, "यह कहना गलत है कि इमरजेंसी का मतलब पंजाब से कोई भेदभाव होगा. पंजाब जैसी समस्याएं और किसी राज्य में कहां हैं?"

आम आदमी को भी इमरजेंसी विधेयक का औचित्य नजर नहीं आता. फिर जिस अफरातफरी में केंद्र ने इसे संसद में पास करवाया है उससे यह अकाल तख्त के नए मुख्यग्रंथी जसबीर सिंह रोडे की विश्वसनीयता खत्म कर देगा और उन्हीं हितों को नुकसान पहुंचाएगा जिनकी रक्षा का यह दावा करता है. ठीक उस वक्त जबकि इंका नेता उन्हें केंद्र और उग्रवादियों के बीच कड़ी बताकर उनकी प्रशंसा कर रहे थे, रोडे को उग्रवादी खेमे के करीब धकेल दिया गया है. विधेयक पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के सिवा उनके सामने कोई चारा भी नहीं था क्योंकि इससे उदारपंथी सिखों का पक्ष और कमजोर पड़ जाएगा.

इस बीच स्थिति उलझाने के कुछ संकेत भी मिले हैं. मसलन पिछले पखवाड़े अमृतसर में सीआरपीएफ के दर्जनों जवान रेत के बोरों के पीछे से चुपचाप तमाशाई बने देखते रह गए कि नीले चोगों में करीब 40 उग्रवादी हाथों में राइफलें उठाए स्वर्ण मंदिर से निकले और रोडे के निवास की ओर जाती सीढ़ियों पर चढ़ गए. वहां रोडे उन्हें सरोपा भेंट करने वाले थे. जवानों ने उस समय भी कोई गोली नहीं चलाई जब ये उग्रवादी लौटकर परिसर के एक दूसरे गेट पर आ खड़े हुए.

इस ढुलमुल नीति की सबसे बढ़िया व्याख्या यही हो सकती है कि केंद्र ने रोडे से उम्मीदें नहीं छोड़ी हैं. गृह मंत्रालय निर्दोष व्यक्तियों की हत्या पर रोडे द्वारा बार-बार अभिव्यक्त 'चिंता' से प्रभावित लगता है. लेकिन ऐसे वक्त में जब रोडे पर खालिस्तान की मांग का समर्थन करने का बेतरह दबाव पड़ रहा है, इमरजेंसी विधेयक उनके लिए मुश्किलें ही पैदा करेगा. विभिन्न गुटों में अपना समर्थन बनाने के प्रयास में रोडे तलवार की धार पर चल रहे हैं. खालिस्तान की मांग के बारे में खास तौर पर पूछे जाने पर वे कहते हैं, "पंथ के सभी धड़े अगर इसके लिए मांग करें तो मैं इसमें बिल्कुल बाधा नहीं बनूंगा."

रोडे की मुख्य चिंता 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन होने वाले सरबत खालसा को रोकना है. अगर यह सम्मेलन हुआ तो उग्रवाद समर्थक, भावुक भीड़ अवश्य ही खालिस्तान के समर्थन में प्रस्ताव पास करेगी जो कि मुख्यग्रंथियों पर भी लागू होगा. इसलिए रोडे का मत है कि यह धार्मिक समागम तभी बुलाया जाना चाहिए जब 'कौम' पर कोई भारी मुसीबत आ जाए. वे कहते हैं, "सरबत खालसा दिवाली का त्यौहार तो नहीं जो हर साल आता ही है."

उग्रवादी कोई नरम रुख तो अपनाते नहीं दिखते इसलिए अब मूल प्रश्न यह है कि रोडे अगले समागम को कब तक रोके रख पाएंगे. उग्रवादी बैसाखी वाले दिन जोर आजमाइश की कोशिश करेंगे. या फिर वे हत्या की वारदातों में इस कदर वृद्धि कर सकते हैं कि केंद्र को मजबूर होकर पुलिस कार्रवाई तेज करनी पड़े. रोड़े यदि शांति स्थापित करने के केंद्र के ताजा प्रयासों को उग्रवाद की लपटों से बचाना चाहते हैं तो दोनों हालात में यह काम उनके लिए बेहद कठिन होगा.

—शेखर गुप्ता और विपुल मुद्गल, अमृतसर में

सीआरपीएफ के शिविर पर आरपीजी-7वी रॉकेट फेंकना इस बात का संकेत है कि उग्रवाद बड़ी बगावत में तब्दील हो रहा है

यूएनआई

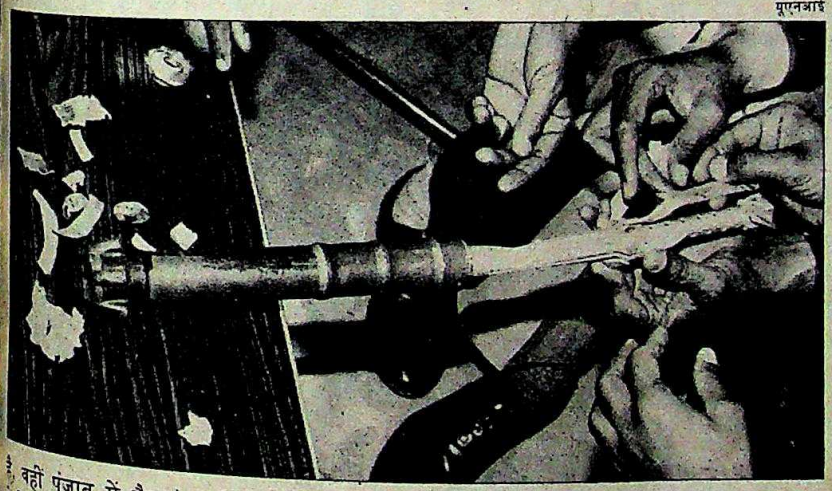

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मोहन अग्रवाल/नई दुनिया

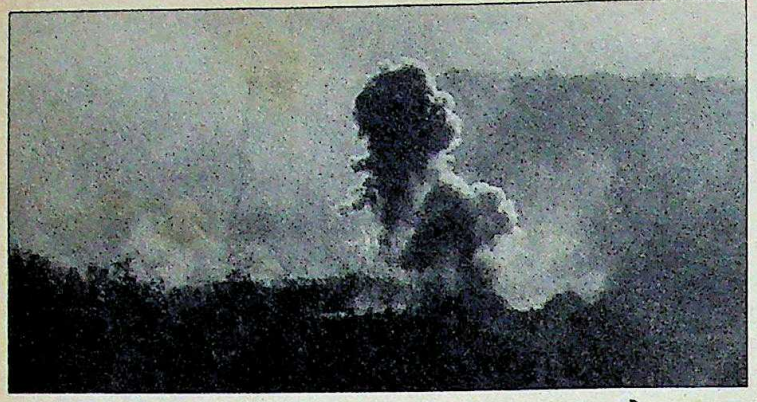

एक शस्त्रागार से उठता धुआं

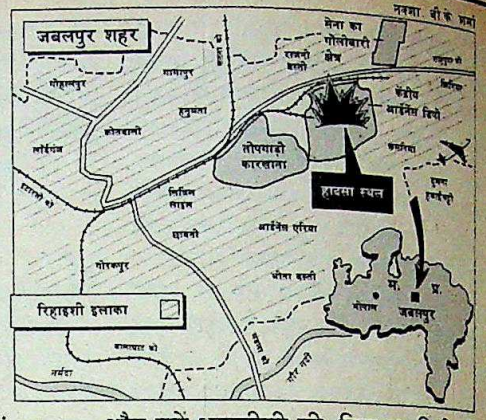

जबलपुर

भयानक हादसा

अग्निकांड में दो शस्त्रागार स्वाहा

एक छोटी-सी चिनगारी भड़की और फिर देखते ही देखते बारूदी विस्फोटों का जैसे दावानल फैल गया. करीब साढ़े आठ लाख आबादी वाला शहर जबलपुर बुरी तरह दहल गया. 23 मार्च की शाम 4 बजकर 10 मिनट पर भड़की इस चिनगारी से देश के एक प्रमुख शस्त्रागार सेंट्रल आर्डीनेंस डिपो (सीओडी) में आग लग गई. इसके बाद आसमान गुंजा देने वाले धमाकों का जो सिलसिला शुरू हुआ तो डिपो के आसपास रहने वाले लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए.

एशिया के सबसे बड़े माने जाने वाले एक शस्त्रागार समेत दो शस्त्रागार स्वाहा हो गए. छोटी, मध्यम और लंबी दूरी की मिसाइलें व ढेरों दूसरे हथियार अग्नि की भेंट चढ़ गए. संतोष की बात सिर्फ यही रही कि 10 लोग ही घायल हुए.

हादसा क्यों हुआ यह पता लगने में शायद कुछ हफ्ते लग जाएं. वैसे गैर-कानूनी घोषित खालिस्तान कमांडो फोर्स ने इसकी जिम्मेदारी तो ली है लेकिन जबलपुर में तैनात सैनिक अधिकारी इस दावे को एक मजाक ही मानते हैं. मध्य प्रदेश, बिहार और ओडीसा क्षेत्र के जनरल अफसर कमांडिंग मेजर जनरल प्रीतम सिंह वर्मा कहते हैं, "यह दावा तो बकवास ही लगता है." लेकिन जांच अदालत तोड़फोड़ की कार्रवाई की संभावना पर भी विचार करेगी.

हादसे के कुछ दिनों बाद भी सबूत नहीं जुटाए जा सके हैं. हर ओर हथियारों के टुकड़े बिखरे पड़े हैं. उस इलाके में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं, सैनिक अधिकारियों को भी नहीं. पूर्व सैनिक अधिकारी और कभी सीओडी के इंचार्ज रह चुके इंका सांसद अजय मुशरान ने घटना-स्थल का दौरा करने के बाद बताया, "अभी 10-15 दिन तक तो कोई वहां जा भी नहीं सकेगा." वे कहते हैं, "असली वजह तो उन शस्त्रागारों की सफाई के बाद ही पता चल सकेगी."

जबलपुर के तकरीबन एक चौथाई इलाके (372 वर्ग किलोमीटर) में प्रति-रक्षा प्रतिष्ठान फैले हुए हैं. सीओडी के अलावा शहरी क्षेत्र में तोपगाड़ी कारखाना, भारी वाहन कारखाना और आयुध कारखाना भी है. 50 वर्ग किलोमीटर में फैले सीओडी में 30 शस्त्रागार हैं जो 40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं. ये शस्त्रागार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए हैं. हर शस्त्रागार की तीन दीवारें चट्टानों की बनी हैं. दरवाजे दोहरे फौलादी कपाटों के बने हैं और छतें आरसीसी की, जिन पर मिट्टी की चार से पांच फुट मोटी तह है. और छतें इस तरह की हैं कि ऐसा कोई हादसा होते ही फट जाएं और भीतर बना दबाव तुरंत बाहर निकल जाए. हर शस्त्रागार में 1,000 टन असलहा रखा जा सकता है. हरेक में पानी के फुहारे लगे हुए हैं. भीतर ताप बढ़ने से ही फुहारे सक्रिय हो जाते हैं.

शस्त्रागारों के समानांतर रेल पटरी बनी हुई है. बाहर भेजे जाने वाले हथियार ढके हुए प्लेटफार्म पर रखे जाते हैं. 23 मार्च को हादसे की शुरुआत ऐसे ही एक प्लेटफार्म के पास से हुई. चिनगारी का पता चलने के तुरंत बाद ही शस्त्रागार नंबर-20 के पास विस्फोट हो गया. सीओडी के कर्मचारी नौ दिन से हड़ताल पर थे और प्लेटफार्म पर गोला-बारूद का बड़ा जखीरा पड़ा था.

24 मार्च को तड़के जब दोनों शस्त्रागारों की छतें धंस गईं तो धमाकों की आवाज मीलों तक सुनी गई. आसपास के कई गांवों को खाली करा दिया गया. जिला प्रशासन हरकत में आ गया. विस्थापितों की रिहाइश का इंतजाम किया गया.

घर छोड़कर भागे गांववाले

राजेंद्र जैन

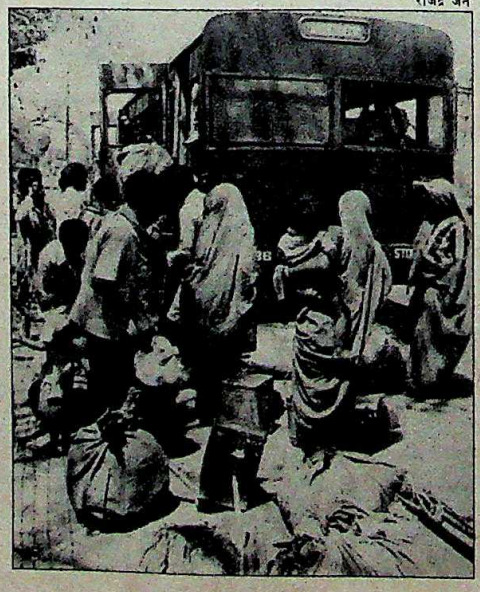

सेना नुकसान का अनुमान लगाने में जुट गई है, जो कई करोड़ तक हो सकता है. रक्षा उत्पादन राज्यमंत्री शिवराज पाटील के लोकसभा में 24 मार्च को दिए बयान के मुताबिक मिसाइलों के अलावा 105 किलोमीटर इन्फैंट्री फील्डगन और 106 मिमी रिक्वाइलेस गन का बारूद भी नष्ट हुआ.

सेना के इस नुकसान पर जबलपुर के लोग आंसू नहीं बहा रहे हैं पर उन्हें यह दहशत भरा एहसास हो गया है कि वे जैसे ज्वालामुखी के मुहाने पर रह रहे हैं. हादसे के तुरंत बाद जबलपुर का दौरा करके मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने सीओडी के आसपास की बस्तियां हटाने का निर्देश दिया है. जाहिर है गैस हादसे से जले अर्जुन सिंह फूंक-फूंक कर कदम रखेंगे.

—नरेंद्र कुमार सिंह, जबलपुर में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नक्सली संगठन

बदलते तेवर

'बुलेट' नहीं 'बैलेट' मानेंगे

लगता है सत्ता या व्यवस्था परिवर्तन के लिए नक्सली भी 'बुलेट' की जगह 'बैलेट' का महत्व स्वीकार करने लगे हैं. भारत जैसे देश में गुरिल्ला युद्ध चलाना, उससे सत्ता पर कब्जा जमाना और फिर व्यवस्था बदलना उन्हें अब संभव नहीं लगता. दो सौ से अधिक नक्सली संगठनों को मिलाकर बने इंडियन पीपुल्स फ्रंट (आईपीएफ) का तीसरा सम्मेलन उत्तर भारत की नक्सली राजनीति में इसी बदलाव का सूचक था. पिछले विधानसभा चुनाव में बिहार में कुछ सीटों पर चुनाव लड़कर हारने वाला यह फ्रंट अब संसदीय राजनीति में ज्यादा तैयारी के साथ उतरने का निश्चय कर चुका है.

दिल्ली के शाह ऑडिटोरियम में 20 से 23 मार्च तक चले इस सम्मेलन में संगठन की तीखी अंदरूनी झड़पें भी दिखाई दीं. चुनावी राजनीति में उतरने की तैयारी का विरोध भी हुआ. कई प्रस्तावों पर स्पष्ट मतविभाजन था. लेकिन सम्मेलन के बाद संगठन का जो रूप उभरा वह पहले से ज्यादा एकीकृत था.

और इसकी सबसे बड़ी वजह थी आईपीएफ द्वारा खुद को एक मोर्चे की जगह राजनैतिक संगठन बनाने का फैसला. सम्मेलन का उद्घाटन फ्रंट के अध्यक्ष वेणुगोपाल सुब्बाराव ने किया और उद्घाटन भाषण चेयरमैन तथा प्रसिद्ध नक्सली नेता नागभूषण पटनायक ने दिया.

508 चुने हुए प्रतिनिधियों और 120 पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में 54 पेज की राजनैतिक-सांगठनिक रिपोर्ट रखी गई. 59 लोगों ने इस पर अपनी राय रखी और कुल 69 संशोधन मंजूर किए गए.

इनमें संगठन के पूर्व सचिव आनंदस्वरूप वर्मा के दो संशोधन भी थे. उनका कहना था कि आईपीएफ भूमिहीन किसानों के संघर्ष और सामंतवाद विरोध की राजनीति पर आधारित था पर इस 54 पेज के दस्तावेज में इन बातों का जिक्र भी नहीं है. उन्होंने बताया, "आईपीएफ धीरे-धीरे संसदवाद के दलदल में फंसता जा रहा है. चुनाव को ध्यान में रखकर ही हर फैसला लेना और बुनियादी मकसद को दरकिनार करना ही दलदल में फंसना है."

पर इस बीच एक और बदलाव हुआ. उत्तर भारत का सबसे बड़ा नक्सली ग्रुप भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) (विनोद मिश्र गुट) ने अपनी राजनैतिक दिशा बदली है. आईपीएफ के गठन के साथ ही यह कहा जाता रहा है कि इसके पीछे विनोद मिश्र गुट का हाथ है. इस बार आईपीएफ के सम्मेलन स्थल पर भूमिगत विनोद मिश्र गुट के चौथे सम्मेलन की रिपोर्ट भी बिक रही थी. रिपोर्ट में मिश्र ने एक 'पीपुल्स फ्रंट' (इंडियन शब्द इसमें नहीं है) बनाने का दावा किया है. साथ ही इस फ्रंट में उत्तराखंड मोर्चे के शामिल न होने की बात कहकर एक तरह से स्पष्ट कर दिया गया है कि (मिश्र गुट का) 'पीपुल्स फ्रंट' ही दरअसल इंडियन 'पीपुल्स फ्रंट है. क्योंकि आईपीएफ पर एक गुट के वर्चस्व के कारण जो संगठन उससे अलग हुए उत्तराखंड मोर्चा भी उनमें से ही एक था.

नक्सली अब गुरिल्ला युद्ध में कामयाबी नहीं देखते. इसलिए वे संसदीय राजनीति में उतर रहे हैं

आईपीएफ के कुछ समर्थकों का कहना है कि ऐसे दावे करने से संगठन का सत्यानाश हो जाएगा क्योंकि मिश्र गुट ने हाल तक हुई जमींदारों की हत्या का जिम्मा अपने ऊपर लिया है. अगर वह आईपीएफ को अपना कहे और संगठन इस पर चुप बना रहे तो यह सरकार के हाथ में बंदूक पकड़ा देने के समान ही होगा.

मजेदार बात यह है कि फ्रंट ने 'राजीव हटाओ' को ही अपना मुख्य नारा बनाया है. वह इंका को सांप्रदायिकता की जड़ मानते हुए उसके विरोध के लिए भाजपा और हिंदू शिवसेना जैसे संगठनों से हाथ मिलाने को भी तैयार है. राजीव सरकार का विरोध करने के लिए फ्रंट ने 19 से 26 अप्रैल तक बड़े पैमाने पर जेल भरो अभियान चलाने का फैसला किया.

अभी तक भारत के मार्क्सवादी दल जाति को आधार बनाकर राजनीति की बात नहीं करते थे. पर पहली बार लोहिया, अन्नादुरई और अंबेडकर की तरह 'ब्राह्मणवाद का विरोध' करने का फैसला भी आईपीएफ ने किया. अमेरिका से आकर भारत में सामाजिक अध्ययन करने वाली गेल ऑमवेट ने भी इस फैसले को एकदम सही बताया.

अभय शर्मा/चौथी दुनिया

नागभूषण पटनायक (माइक पर): परिवर्तित विचार

वैसे एक लाख 30 हजार रुपए के खर्च से (जिसमें 10 हजार का घाटा रह गया) हुए इस सम्मेलन ने जो सेंट्रल एक्जिक्यूटिव कमेटी चुनी वह नौजवान और उत्साही लोगों की है. इसमें संगठन की दोनों पत्रिकाओं 'जनमत' तथा 'वायस ऑफ आल्टरनेटिव' के संपादक रामजी राय और दीपंकर घोष भी हैं.

आईपीएफ का पिछला सम्मेलन इंदिरा गांधी की हत्या के अगले दिन ही कलकत्ता में हुआ था. उस समय वहां तक पहुंचने के लिए पंजाब के तीन प्रतिनिधियों को अपनी दाढ़ी-बाल काटने पड़े थे. इस बार उन्हीं में से एक कामरेड हाकम सिंह की सफेद दाढ़ी फिर लहराने लगी है. पिछली बार उनके साथ गए साथियों को मंच पर बैठे हाकम सिंह की फहराती दाढ़ी नया उत्साह पैदा होने का प्रतीक लग रही थी

—अरविंद मोहन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जयपुर राजघराना

महल की लड़ाई सड़क पर

पूर्व राजा ने प्रधानमंत्री से जान की हिफाजत की मांग की

तख्त के दावेदारों में ताज भी उलझ गया है. पिछले महीने जयपुर राजघराने के एक पक्ष ने इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड के ताज ग्रुप के जरिये सवाई माधोपुर लॉज और जयपुर का रामगढ़ लॉज दूसरे पक्ष से हथिया लिए. ताज ग्रुप वालों ने दोनों लॉज में कार्यरत पूर्व महाराजा भवानी सिंह के लोगों को खदेड़ दिया. सवाई माधोपुर में तो दोनों ओर से खूब लाठियां भी चलीं और पांच लोग घायल हो गए.

ताज को लपेट में लेने वाले इस झगड़े के बीज तो 1972 में ही पड़ गए थे. भवानी सिंह और उनके तीनों सौतेले भाइयों— जय सिंह, पृथ्वी सिंह और जगत सिंह ने उस साल 1 अक्तूबर को जयपुर के रामबाग पैलेस में साझे तौर पर एक पांच सितारा होटल शुरू किया था. इसकी व्यवस्था का भार 2001 तक के लिए ताज ग्रुप को सौंपा गया था. भवानी सिंह के पिता महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय की मृत्यु तक रामबाग पैलेस उनका रिहायशी महल था. अब भवानी सिंह ने अपने भाइयों पर होटल के हिसाब-किताब में भारी हेराफेरी का आरोप लगाया है.

कथित हेराफेरी की शुरुआत उस समय हुई जब होटल के निदेशक मंडल की बैठक में जगत सिंह ने अपने हिस्से का एक इक्विटी शेयर जयमहल पैलेस होटल के नाम कर दिया. जयमहल पैलेस जगत सिंह की अपनी जायदाद है. इस इक्विटी शेयर के हस्तांतरण पर भवानी सिंह ने आपत्ति की. भवानी सिंह की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में कहा गया कि होटल दो करोड़ रुपए सालाना से ज्यादा का धंधा करता है जबकि वार्षिक आय 40 लाख रुपए से ज्यादा नहीं बताई गई. मामला अदालत के विचाराधीन है. दूसरी ओर पिछले साल 30 दिसंबर को होटल के निदेशक मंडल की बैठक बुलाकर सदस्यों ने निदेशक भवानी सिंह को उनके पद से हटाकर गायत्री देवी को निदेशक नियुक्त कर दिया हालांकि होटल में राजमाता का कोई शेयर नहीं है.

ताजा घटनाओं के बारे में ताज ग्रुप के एक प्रवक्ता का कहना है कि दोनों लॉज 20 वर्ष के लिए लीज पर लिए गए हैं जो रामगढ़ लॉज प्रा. लि. के प्रबंधकों ने रामबाग पैलेस प्राइवेट लिमिटेड को दिए और पैलेस के निदेशक जय सिंह ने ताज ग्रुप को. प्राप्त जानकारी के अनुसार यह दोनों लॉज ताज ग्रुप के तालमेल अधिकारी रायसर के ठाकुर जेत सिंह व राजीव सेठ तथा गायत्री देवी, उनके पुत्र जय सिंह और जगत सिंह की मौजूदगी में देने का फैसला किया गया. ताज ग्रुप वालों ने दोनों लॉज की सफाई व मरम्मत का कार्य भी शुरू करवा दिया है.

कब्जा होने के बाद भवानी सिंह रामगढ़ व सवाई माधोपुर भी गए. दोनों स्थानों पर हुए झगड़ों की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाई गई है जिसमें पूर्व महाराजा और ताज ग्रुप के लोगों को पार्टी बनाया गया है. पर भवानी सिंह का आरोप है कि "ताज ग्रुप वालों ने कई गुंडों को वहां भेजकर कब्जा करना चाहा. सवाई माधोपुर में तो उन्हें भगाने के लिए कई हजार लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी. झगड़ा भी हुआ."

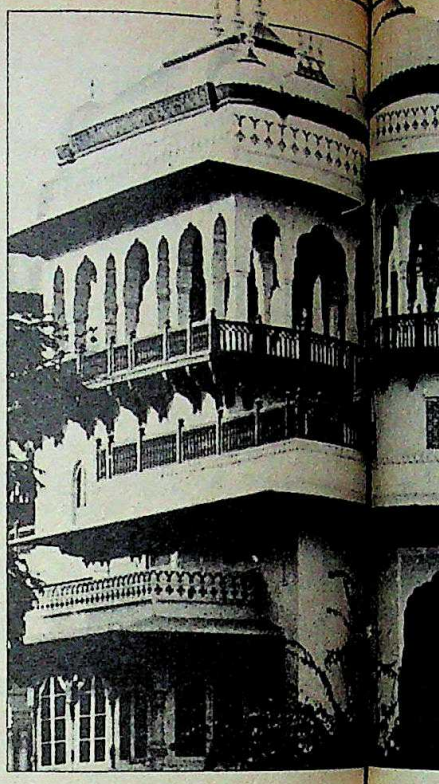

उनके ही एक प्रवक्ता का कहना है कि ताज ग्रुप वालों ने इन दोनों लॉज पर जय सिंह की मिलीभगत से कब्जा किया है ताकि इसकी आड़ में रामबाग पैलेस में किए गए लाखों के घपलों को छिपाया जा सके. प्रवक्ता के अनुसार रामगढ़ लॉज पर कई वर्षों से भवानी सिंह की पत्नी रानी पद्मिनी का कब्जा है और इसे दिल्ली हाईकोर्ट में दूसरे पक्ष ने भी स्वीकार किया है.

जमीन जायदाद के बंटवारे को लेकर होने वाले विवाद जयपुर राजघराने के लिए नए नहीं हैं. इन विवादों की खास वजह है जयपुर राजघराने की विशाल संपदा, जिनकी कीमत 1,000 करोड़ रुपए आंकी गई है. इससे संबंधित चार मुकदमे दिल्ली हाईकोर्ट में और एक राजस्थान हाईकोर्ट में चल रहा है.

विवाद के मुख्य प्रतिद्वंद्वी सवाई मान सिंह द्वितीय के पहले वैध पुत्र भवानी सिंह और उनकी सौतेली मां राजमाता गायत्री देवी हैं. मोटे तौर पर झगड़ा यह है कि सारी संपत्ति दिवंगत महाराजा के उत्तराधिकारी के रूप में भवानी सिंह की निजी संपत्ति है या वे संयुक्त और अविभक्त हिंदू परि

राजमाता गायत्री देवी की मौजूदगी में ही दोनों लॉज होटल वालों को लीज पर देने का फैसला हुआ

भवानी सिंह का आरोप है कि ताज ग्रुप वालों ने दोनों लॉज पर गुंडे भेजकर कब्जा जमा लिया

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

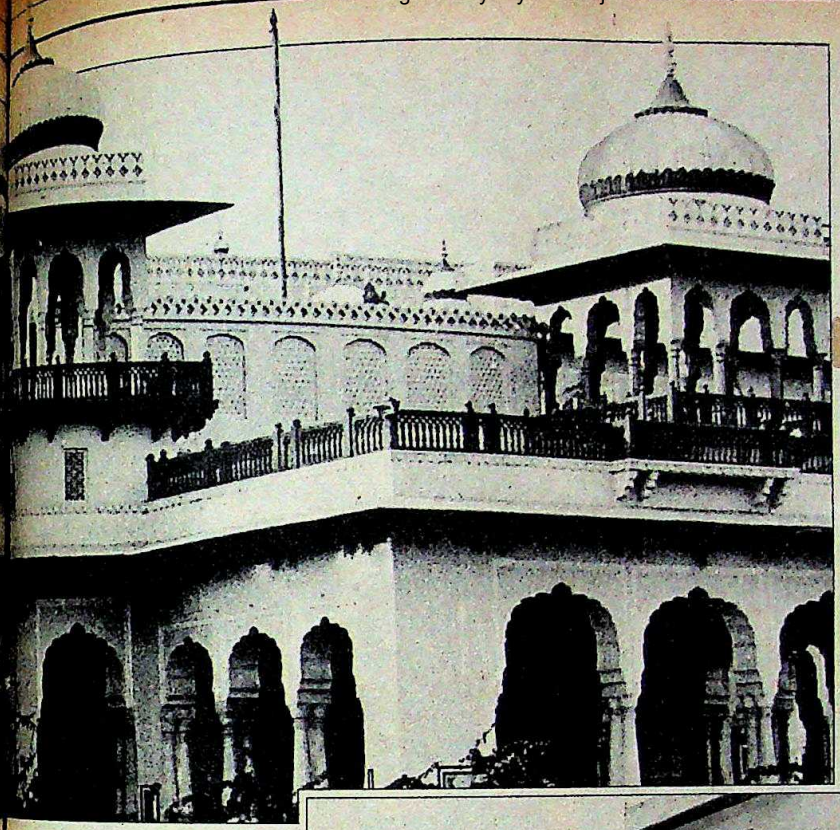

रामगढ़ लॉज (दाएं); और होटल रामबाग पैलेस: झगड़े की जड़

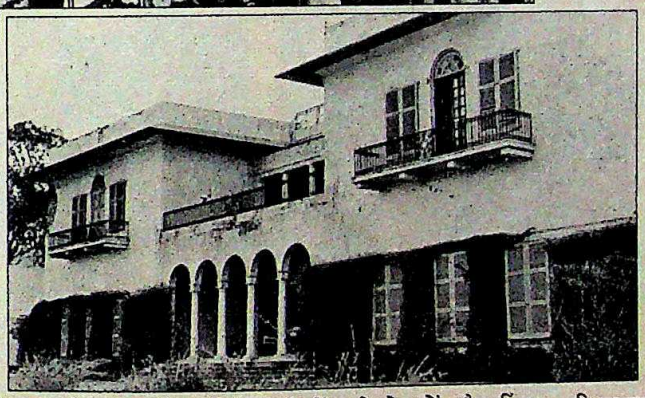

कार के कर्ता के रूप में इसके स्वामी हैं. राजघराने की करोड़ों की संपत्ति में चल व अचल दोनों तरह की संपत्ति है. अचल संपत्ति में रामबाग पैलेस, जयगढ़, सिटी पैलेस, तख्तेशाही महल, राजमहल पैलेस, मोती डूंगरी महल, खातीपुरा आउट हाउस, आरामगाह और इसके आसपास की भूमि, रामगढ़ क्वार्टर्स व रामगढ़ फार्म की जमीन और खातीपुरा फार्म की कृषि भूमि है. इसके अलावा चल संपत्ति में आभूषण, संपत्ति शुल्क से मुक्त पाए मैडल, गाड़ियां, नकद व बैंक बैलेंस, कंपनियों के शेयर, चांदी के बर्तन, कीमती फर्नीचर, अमूल्य कलाकृतियां वगैरह शामिल हैं.

जयपुर राजघराने के ढाई सौ साल के इतिहास में यह किंवदंती रही है कि जिस दिन राजगद्दी पर वैध पुत्र बैठेगा, उस दिन से इसका नाश शुरू हो जाएगा. शायद यही वजह रही है कि अब तक राजगद्दी पर बैठने वाले सभी गोद लिए पुत्र ही थे. पता नहीं इस किंवदंती में कितनी सचाई है पर भवानी सिंह इस राजगद्दी पर बैठने वाले पहले वैध पुत्र हैं और शायद आखिरी राजा भी.

इस किंवदंती के चलते ही राजघराने में विवाद उभरा. राजमाता गायत्री देवी और जय सिंह ने भवानी सिंह से शेयरों और हिंदू अविभक्त परिवार के बंटवारे का अनुरोध किया. लेकिन भवानी सिंह ने इसके लिए साफ मना कर दिया. उनका तर्क था कि सवाई मान सिंह की संपत्ति हिंदू अविभक्त परिवार की नहीं बल्कि अकेले उनकी है, इसलिए उसके बंटवारे का सवाल ही नहीं उठता. सवाई मान सिंह की मृत्यु के बाद 25 जुलाई 1970 को तत्कालीन राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 366 (22) के तहत उन्हें जयपुर के शासक के रूप में मान्यता दी थी. राजगद्दी का वारिस होने के कारण भवानी सिंह राजघराने की संपत्ति के वारिस भी बन गए. दूसरी तरफ दिवंगत महाराजा की दूसरी पत्नी किशोर कंवर के दूसरे पुत्र पृथ्वी सिंह का कहना है कि सवाई मान सिंह स्वयं भी उस संयुक्त हिंदू परिवार के कर्ता और सदस्य थे जिसमें उनके चारों पुत्र, पृथ्वी सिंह की पत्नी और पुत्र विजित तथा जगत सिंह की पत्नी भी सदस्य थीं. उनके अनुसार आयकर, संपदा कर, धन कर, स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम वगैरह में भवानी सिंह ने सवाई मान सिंह को संयुक्त परिवार का कर्ता बताया था और इसी हिसाब से अपने आयकर रिटर्न भी भरे थे.

राजमाता गायत्री देवी के सगे पुत्र जगत सिंह ने भी दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करके भवानी सिंह पर संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति को गैर-कानूनी रूप से बेचने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा है कि भवानी सिंह ने कई संपत्तियों से होने वाली आय के बारे में परिवार के दूसरे सदस्यों को बेखबर रखा और बार-बार मांगे जाने के बावजूद आय का हिसाब नहीं दिया. उन्होंने अदालत से मांग की है कि पारिवारिक संपत्ति के विभाजन की अनुमति देकर परिवार के दूसरे सदस्यों को हिस्सा दिलवाया जाए.

पर भवानी सिंह कहते हैं, "संपत्ति विवाद बेबुनियाद है. मेरे स्वर्गीय पिता ने संपत्ति का बंटवारा पहले ही कर दिया था. उन्होंने बहुत-सी जागीरें और जमीन मेरे भाइयों को तथा दुर्गापुरा फार्म व भवन मेरी सौतेली मां को दिए. मेरे नाम अलग से कुछ नहीं था क्योंकि उनका विचार था कि उत्तराधिकारी के नाते शेष संपत्ति पर मेरा अधिकार रहेगा. जयसिंह ठिकाना झिलाई और जगत सिंह ठिकाना ईसरदा की गोद चले गए थे. परंतु अब सौतेली मां और भाई मेरी संपत्ति पर अवैध तरीके से अधिकार करना चाहते हैं."

बहरहाल जयपुर राजघराने की लड़ाई अब प्रधानमंत्री राजीव गांधी तक भी पहुंच गई है. ताजा घटनाओं के बाद भवानी सिंह ने प्रधानमंत्री को तार भेजकर जान की सुरक्षा की मांग की है. पूर्व महाराजा ने इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर से मुलाकात की और खत भी लिखा है. उनका आरोप है कि "स्थानीय पुलिस और प्रशासन का काम करने का तरीका बहुत धीमा है." विडंबना है कि रियासती राज में जनता जिस राजा के पास जान की सुरक्षा की गुहार लेकर जाती थी आज वैसे ही एक 'राजा' ने प्रधानमंत्री से सुरक्षा की मांग की है.

सारे विवादों का फैसला तो अब अदालत के विचाराधीन है पर इन पारिवारिक झगड़ों का कारण रनिवासों में पलते षड्यंत्र, राजमहल की सुनहरी दीवारों के पीछे छिपे स्वार्थ और उनमें पल रही विलासिता ही है. राजपरिवार दुखी हो या न हो, जयपुर वाले 'राजा' की टोपी उतरते देखकर बहुत दुखी हैं.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बंबई

शेर की गुर्राहट

सांप्रदायिक सद्भाव खतरे में

शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे की मांग के कारण बंबई में बसे एक लाख सिखों के सामने भयानक संकट आन खड़ा हुआ है. 19 मार्च को उन्होंने पत्रकार वार्ता की, जो बाद में लगभग एक धार्मिक अदालत में तब्दील हो गई. इसमें शिवसेना प्रमुख ने शहर के सिखों को एक माह का अल्टीमेटम दे डाला. उन्होंने कहा कि इस मियाद के भीतर वे एक प्रतिनिधिमंडल अमृतसर भेजकर ग्रंथियों से उग्रवादियों के खिलाफ हुकुमनामा जारी करवाएं, नहीं तो वे उनका सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार करवा देंगे.

सभी फोटो: नामम भोजानी

सिख नेता और (दाएं) बाल ठाकरे: अटपटी मांग

ठाकरे के इस अभूतपूर्व एलान में छिपे खतरे बहुतों ने तुरंत भांप लिए. बंबई इंका के अध्यक्ष मुरली देवड़ा ने इसे 'विशुद्ध ब्लैकमेल' निरूपित किया और वायदा किया कि यदि बहिष्कार की धमकी पर अमल हुआ तो वे सिख बिरादरी को हर मुमकिन मदद देंगे. बंबई के पूर्व महापौर मनमोहन सिंह बेदी कहते हैं, "इससे लोग और बंट जाएंगे." लेकिन ठाकरे को इसका कोई मलाल नहीं है. वे कहते हैं, "यह तो केवल आर्थिक बहिष्कार है. हम सिखों की हत्या तो करने नहीं जा रहे."

ठाकरे ने अपनी पत्रकार वार्ता की शुरुआत एक प्रश्नावली बांटकर की. इसमें उन्होंने सिखों से 'खालिस्तान' का समर्थन न करने और आतंकवादियों को पैसा न देने का आश्वासन मांगा. बिना किसी सबूत के उन्होंने आरोप लगाया कि बंबई के सिखों ने भिंडरांवाले के लिए 37 लाख रुपए इकट्ठे किए थे. वहां मौजूद सिख नेताओं ने इस आरोप का तुरंत खंडन किया. पर गुरु सिंह सभा के उपाध्यक्ष कुलवंत सिंह कोहली ने कहा, "1982 में भिंडरांवाले के लिए कुछ पैसा इकट्ठा किया गया था, लेकिन उस वक्त एक धर्म प्रचारक के रूप में ही जानते थे."

यंग मेंस सिख एसोसिएशन के अध्यक्ष और बंबई के खालसा कॉलेज के ट्रस्टी कुलदीप सिंह चड्ढा ने कहा कि अमूमन सभी सिख खालिस्तान का विरोध करते हैं. लेकिन पंजाब में हो रही घटनाओं को प्रभावित करने में अपनी असमर्थता जताते हुए कोहली ने कहा, "हम उनसे सिर्फ गुजारिश ही कर सकते हैं. हम सर्वोच्च तखत के ग्रंथियों को आदेश कैसे दे सकते हैं?"

पर ठाकरे अपनी इस बात पर अड़े हैं कि स्थानीय व्यापारी पंजाब के आतंकवादियों को हर महीने लगभग एक करोड़ रुपए भेज रहे हैं. जब पत्रकार वार्ता में मौजूद सिखों ने इस दावे के समर्थन में कुछ सबूत चाहे तो ठाकरे के पास कोई जवाब नहीं था.

ठाकरे के विस्फोटक एलानों के बाद सिखों ने अलग से पत्रकार वार्ता करके ठाकरे से अनुरोध किया कि वे अमृतसर के लिए प्रतिनिधिमंडल की अगुआई करें. लेकिन ठाकरे ने प्राणभय से यह प्रस्ताव ठुकरा दिया. सिखों ने उन्हें पूरी सुरक्षा देने का वायदा किया तो उन्होंने कहा, "जाहिर है कि वे उग्रवादियों को काबू में कर सकते हैं. वरना आतंकवादियों की हिंसा से मेरी सुरक्षा का आश्वासन वे क्यों कर देते?"

शहर में सिखों की सर्वोच्च संस्था गुरु सिंह सभा ने स्वर्ण मंदिर में एक पत्र भेजकर मुख्यग्रंथी जसबीर सिंह रोडे से बेकसूरों की हत्याओं के खिलाफ हुकुमनामा जारी करने की गुजारिश की है. पर इतना तय है कि ठाकरे के बयान से स्थानीय सिखों को बड़ी चोट पहुंची है. एक प्रमुख व्यापारी गुरचरण सिंह सेठी कहते हैं, "ठाकरे देशभक्ति का झंडा अपने ही चारों ओर लपेटकर हालात का फायदा उठा रहे हैं. पर उन्हें याद रखना चाहिए कि अकेले वे ही देशभक्त नहीं हैं."

बंबई का सिख समुदाय काफी संपन्न है और वे ऑटो, कल-पुर्जों, परिवहन, होटल और वस्त्र उद्योग पर छाए हुए हैं. शहर में सिखों के 400 रेस्तरां हैं और पूरे समुदाय की कुल संपत्ति कई सौ करोड़ रुपए कूती जाती है. हालांकि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उत्तरी भारत में सिखों के खिलाफ उठी हिंसा की तूफानी लहर से शहर अछूता ही रहा. लेकिन इसके दो वर्षों बाद जनरल वैद्य की हत्या के बाद उन्हें हिंदू समुदाय की नाराजगी का सामना करना पड़ा. अगस्त 1986 में छुरेबाजी की बहुत सी घटनाएं हुईं लेकिन राज्य सरकार ने हमलावरों की खोजबीन में बहुत कम दिलचस्पी ली. इसी से उत्साहित होकर ठाकरे को लगा कि स्थानीय सिखों के खिलाफ कड़ा रवैया अख्तियार करने से उनकी लोकप्रियता में खासा इजाफा होगा.

रचनात्मक आतंकवाद (चाहे इसका जो भी मतलब हो) में यकीन रखने वाले ठाकरे इस बात पर अड़े हुए हैं कि सिखों को उनकी तय की हुई मियाद बीतने यानी 19 अप्रैल से पहले-पहले अपने नुमाइंदों को अमृतसर भेज देना चाहिए. पर जब तक ठाकरे खुद भी चलने को राजी न हों, सिख ऐसा नहीं करना चाहते. और ठाकरे के साथ चलने की संभावना कम ही नजर आती है. पर ठाकरे ने संकेत दिया है कि वे सिखों के नुमाइंदों के साथ अपने कुछ स्वयंसेवकों को भेज सकते हैं. यदि सामाजिक बहिष्कार की ठाकरे की अपील पर अमल हो गया तो उससे महानगर का सांप्रदायिक सद्भाव तो चौपट होगा ही एक और राज्य में सिखों की जान सांसत में पड़ जाएगी.

—सलिल त्रिपाठी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

एक सनसनीखेज इंटरव्यू

"ज्ञानी जी," हमने कहा, "यदि आपके पास समय हो तो..." "प्रेस के लिए मेरे पास हमेशा समय है," ज्ञानी जी ने कहा. "शुक्रिया! हम आपके विचार जानना चाहेंगे..."

"कौन से विचार?" ज्ञानी जी ने पूछा. "जो कुछ हुआ, मैं उसके बारे में पहले ही 165 दफा बोल चुका हूं..."

"हम जानते हैं, ज्ञानी जी, जानते हैं! हम एक खास इंटरव्यू में मौजूदा विवाद की अंदरूनी कहानी जानना चाहते हैं!"

"मैं खास इंटरव्यू देने के लिए तैयार हूं," ज्ञानी जी ने कहा, "मैंने अपने बगल में यह टेपरिकार्डर रखा हुआ है ताकि आप बाद में मेरी बातों को तोड़-मरोड़कर पेश न कर सकें!"

"क्या आपने इसे चालू कर रखा है, ज्ञानी जी?"

"नहीं, मैं इसे बंद रखता हूं ताकि बाद में आप मेरी कही बातों का जिक्र कर सकें."

"ज्ञानी जी, प्रेस में आजकल जो विवाद चल रहा है उसकी असली वजह क्या है? आपके और प्रधानमंत्री के बीच इतना तनाव और मनमुटाव क्यों चल रहा है?"

"इसकी वजह कोई व्यक्तिगत द्वेष या झगड़ा नहीं है," ज्ञानी जी ने कहा. राजीव 'बीबा मुंडा' (अच्छा लड़का) है. असल समस्या तो यह है कि प्रधानमंत्री और पूर्व राष्ट्रपति के बीच कैसे रिश्ते होने चाहिए— इस बाबत संविधान में साफ-साफ कुछ नहीं कहा गया है. खैर, मैंने इस सवाल पर कानून के कई माहिरों से अध्ययन करवाया जिनकी रिपोर्ट मुझे मिल गई है."

"माहिरों की उस रिपोर्ट का सार-संक्षेप क्या है, ज्ञानी जी?"

"एक पूर्व राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री को बर्खास्त करने का पूरा-पूरा हक है," ज्ञानी जी ने कहा.

हम अचंभे में पड़ गए. हमने पूछा, "क्या सरकार से?"

"नहीं," ज्ञानी जी ने कहा, "अखबार की सुर्खियों से!"

"क्या आप सचमुच ऐसा करने का इरादा भी रखते हैं?"

"अभी मैं कुछ भी तय नहीं कर पाया हूं." ज्ञानी जी ने कहा, "आपको पता है, कुछ लोग, फिलहाल जिनके मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, मुझसे गुजारिश कर रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री को रोजाना अखबार की सुर्खियों से बर्खास्त कर दूं. इन लोगों ने तो मुझे इसके लिए हर तरह की भरपूर मदद देने की पेशकश भी की."

"किस तरह की मदद, ज्ञानी जी?"

"उनका कहना है कि राजीव को सुर्खियों से हटाने के लिए तकरीबन 30 से 40 करोड़ प्रेस बयानों की जरूरत पड़ेगी. उन लोगों ने मुझे इतने बयान तैयार करने का भरोसा भी दिलाया है."

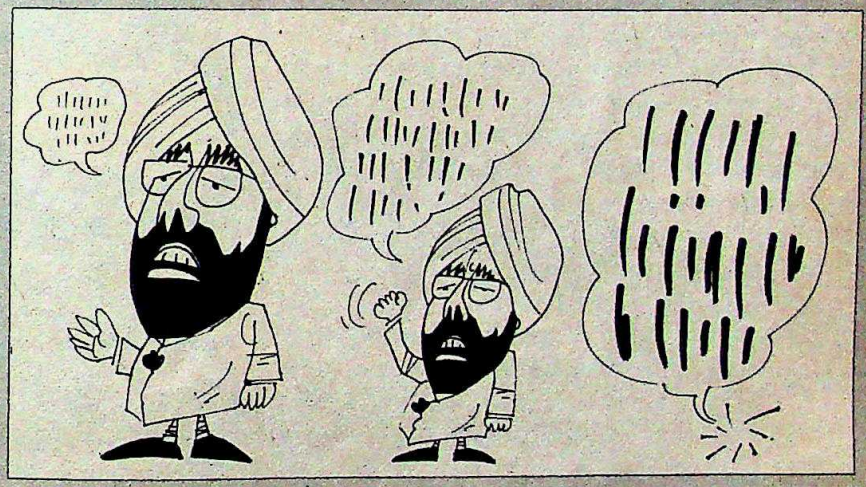

"30 से 40 करोड़ प्रेस बयान!..."

"हो सकता है, मैंने गलत समझा हो," ज्ञानी जी ने हड़बड़ाहट में कहा, "हो सकता है, उन्होंने 30 से 40 लाख बयानों की बात कही हो. मुझे अब ठीक-ठीक याद नहीं आ रहा है."

"ज्ञानी जी, आप प्रधानमंत्री से इतने ज्यादा नाखुश क्यों हैं?"

"राजीव अपनी ताकत की सीमा नहीं जानते. वे पूर्व राष्ट्रपति के विशेषाधिकार हड़प नहीं सकते. हाल ही में उन्होंने बताया था कि अपनी छुट्टियां मनाने के लिए उन्हें किस तरह पैसे खर्च करने पड़े और इसके लिए सरकार पर एक भी पैसे का बोझ नहीं पड़ा. ये सब ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में सिर्फ कोई पूर्व राष्ट्रपति ही बोल सकता है. यदि प्रधानमंत्री ही इस तरह की बातें करने लगेगा तो पूर्व राष्ट्रपति को निभाने लिए कौन-सी भूमिका बची रह जाएगी?"

"ज्ञानी जी, यदि राजीव को अखबारों की सुर्खियों से हटाने का अधिकार आपके पास है तो ऐसा करने से आपको रोक कौन रहा है. कौन-सी ऐसी चीज है जो आपके पांवों (हाथों) में जंजीर डाल रही है, जुबान पर लगाम लगा रही है?"

"फिर राजीव की जगह कौन लेगा?" ज्ञानी जी ने सवाल किया.

"क्या आप खुद उनकी जगह नहीं ले सकते, ज्ञानी जी?"

"मुझे सलाह दी गई कि यदि मैं वैसा करूंगा तो न सिर्फ संविधान बर्बाद हो जाएगा बल्कि देश के हरेक आदमी की व्यवस्था ही गड़बड़ा जाएगी. और सब कुछ तहस-नहस हो जाएगा. व्यवस्था की चूलें ही हिल जाएंगी."

"ज्ञानी जी, क्या आप हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अखबारों में रोजाना छपने वाले आपके प्रेस बयानों से ही देश का संविधान और राजनैतिक प्रणाली बर्बाद हो सकती है? व्यवस्था गड़बड़ा सकती है, समूची प्रणाली का सत्यानाश हो सकता है?"

"नहीं, नहीं, मुझे बताया गया है कि रोजाना छपने वाले मेरे इन धमाकेदार प्रेस बयानों से हरेक का निजी संविधान और हाजमा बर्बाद हो सकता है..."

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar
Format by MAHENDRA RATHORE

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अपनी-अपनी हांकते नेता

हालांकि पूर्वोत्तर भारत में अभी तक बागियों की समस्या ही अहम है पर मसला उलझ रहा है इस इलाके के इंका मुख्य-मंत्रियों के परस्पर विरोधी रवैयों से. नगालैंड के मुख्यमंत्री होकिशे सेमा बर्मा में अड्डा जमाए बैठी नेशनल सोशलिस्ट कौंसिल ऑफ नगालैंड को समझाने-बुझाने में लगे हैं कि वे मुख्यधारा में आ मिलें. दूसरी ओर पड़ोसी राज्य मणिपुर के मुख्यमंत्री जयचंद्र सिंह मानते हैं कि इस संगठन को रास्ते पर लाने के लिए कड़ाई से पेश आना

रमेश मेनन

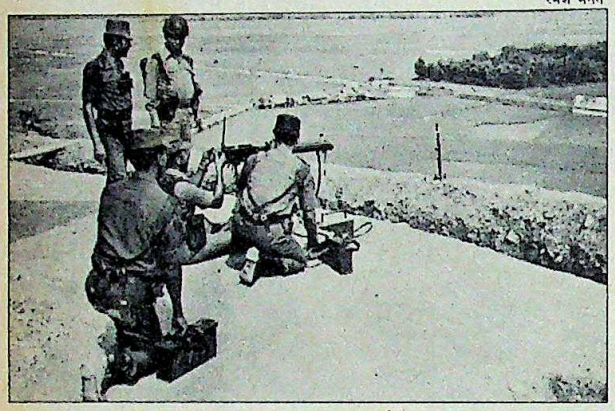

मणिपुर में निगरानी करते सैनिकः अनसुलझी समस्या

होगा. यह संगठन मणिपुर में ही सबसे ज्यादा सक्रिय है.

उधर त्रिपुरा में इंका मुख्यमंत्री सुधीररंजन मजूमदार ने फरवरी में गद्दी संभालते ही कहा था कि गैर-कानूनी ट्राइबल नेशनल वालंटियर (टीएनवी) से कोई बातचीत नहीं होगी. लेकिन अब उनका कहना है कि टीएनवी से बातचीत के लिए तैयार हैं बशर्ते वह भारतीय संविधान को मान ले और 'स्वतंत्र त्रिपुरा' की अपनी मांग छोड़ दे. इस ढुलमुल रवैये से सरकार की विश्वसनीयता कितनी गिरी होगी इसका अंदाज लगाना मुश्किल नहीं है.

पटनायक को प्रमाणपत्र

ओडीसा के सूखाग्रस्त कालाहांडी जिले से आने वाली भुखमरी की खबरें एक अर्से से जानकीबल्लभ पटनायक सरकार को परे-शान किए हुए हैं. लेकिन अब कालाहांडी के जिला जज पी.सी. पंडा की अध्यक्षता में बने एक सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट आ गई है. रिपोर्ट के मुताबिक कालाहांडी में कोई भी भूख से नहीं मरा. इसमें राज्य सरकार के राहत कार्यों की भी तारीफ है.

एक लोकहित याचिका के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने पंडा को कालाहांडी के लोगों की दशा पर छपी रिपोर्टों की जांच की लिए नियुक्त किया था. पंडा ने पिछले महीने अपनी 362 पेज की रिपोर्ट

ईस्टर्न प्रेस एजेंसी

कालाहांडी का एक गांवः सरकारी विजय

दाखिल की. उनका कहना है कि 49 साल से ज्यादा और इससे कम उम्र के लोगों की मौत भुखमरी से नहीं वरन किसी बीमारी से हुई.

पंडा ने यह जांच अकेले अपने ही बूते पर की है. उधर कालाहांडी के विपक्षी विधायक और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता इस रिपोर्ट को धोखा मानते हैं. पर पटनायक कहते हैं कि उन्हें न्यायाधीश की निष्पक्षता पर पूरा भरोसा है और कालाहांडी के जनता विधायक भक्तचरण दास पंडा की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लगा रहे हैं.

आईएएस मैदान में

आईएएस एसोसिएशन की बिहार इकाई केंद्र सरकार की कार्रवाइयों को चुनौती देने के मूड में है. विवाद की वजह है बिहार राज्य विद्युत परिषद के अध्यक्ष जे.सी. जेतली. पिछले साल अक्तूबर तक वे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव थे. राज्य के नौकरशाहों के एक असरदार गुट का आरोप है कि जेतली की सचिव पद पर तरक्की होनी थी पर उन्हें 'प्रतिशोधात्मक' ढंग से पीछे कर दिया गया. उनका कहना है कि केंद्र सरकार की कार्मिक समिति ने भी तरक्की के लिए जेतली के नाम की सिफारिश की थी. पर राजीव गांधी की अध्यक्षता वाली प्रशासनिक सलाहकार समिति (एसीसी) ने उनका नाम तरक्की की फ़ेहरिस्त से निकाल दिया.

कृष्ण मुरारी किशन

जेतलीः सरकार को चुनौती

आरोप है कि यह सब राजीव के एक नजदीकी नौकरशाह के इशारे पर किया गया जो जेतली को नापसंद करता है.

जेतली ने एसीसी के फैसले को केंद्रीय प्रशासनिक पंचाट में चुनौती दी. पंचाट ने मनमर्जी फैसले के अधि-कार के सरकारी तर्क को नामंजूर करते हुए जेतली के मामले को सही ठहराया. अब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है जहां बिहार की आईएएस एसोसिएशन जेतली के मुकदमे को जड़ना चाहता है. उसे दूसरे राज्यों के आईएएस एसोसिएशनों का भी समर्थन प्राप्त है. राज्य के अधिकारियों ने इस बार कमर कस ली है क्योंकि इस तरह की गाज दूसरे पर भी गिर सकती है.

'काबिल' लोगों की छंटाई

राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद आज-कल तमिलनाडु में 'छंटाई अभियान' चल रहा है. पिछले पखवाड़े सरकार ने राज्य के करीब 34,000 में से एक-तिहाई मंदिरों का कामकाज संभालने वाले मानसेवी 'योग्य व्यक्तियों' के पद खत्म कर दिए. 'योग्य व्यक्ति' के पद एम.जी. रामचंद्रन सरकार का एक अजूबा आविष्कार था. जब भी धनी-मानी मंदिरों के पुराने ट्रस्टियों का कार्यकाल खत्म होता उसकी जगह लेने के लिए नया 'योग्य व्यक्ति' तलाश लिया जाता जो सत्तारूढ़ अन्नाद्रमुक का ही आदमी होता.

पर राज्यपाल पी.सी. अलेक्जेंडर के प्रशासन को लगा कि इस पद पर रहने वाले के पास तो बहुत से अधिकार आ जाते हैं यहां तक कि हिंदू धार्मिक व धर्मादा विभाग के कार्यकारी अधिकारियों को भी इन्हीं 'योग्य व्यक्तियों' के मातहत रहना पड़ता था. पर सबसे गंभीर इल्जाम तो यह है कि ये राजनैतिक व्यक्ति मंदिरों की

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

MAKE YOUR HAPPY HOME HAPPIER!

With the MMI range of products.

The MMI modern range of appliances is something we guarantee you'll be very happy with. Ceiling Fans, Fresh Air Fans, Mini-Fans, Exhaust Fans, Cooler Fans and Pumps, Washing Machines, and Geysers. Products that meet the highest standards of quality. With smooth, trouble-free performance. For years together. At very affordable prices.

L.R. Electricals Pvt. Ltd.
1822 A/4, Bhagirath Palace
Delhi-110006 Phone: 234282

Dealership enquiries solicited in unrepresented areas.

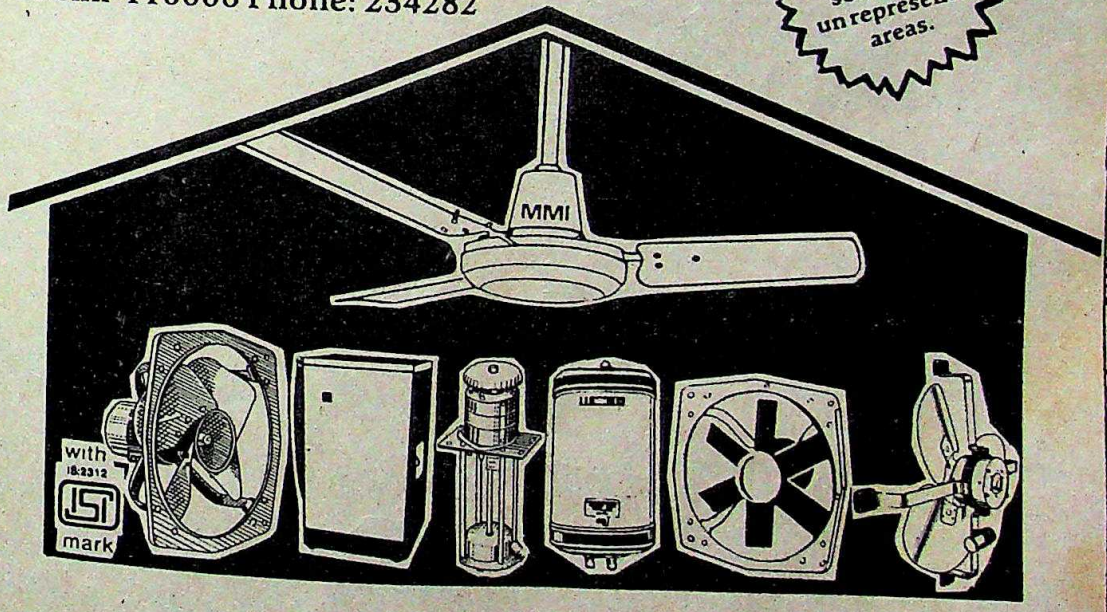

MMI

For happier homes!

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आमदनी पर भी शायद हाथ साफ कर रहे थे.

धर्मादा सचिव के अलूदिया पिल्लई के अनुसार मंदिरों का प्रशासन अब उनके विभाग के अधिकारी खुद चलाएंगे. लेकिन कहना सरल है पर करना कठिन. क्योंकि राज्य में सिर्फ 400 कार्यकारी अधिकारी ही हैं जबकि के खाली पदों की संख्या 2,000 है.

विरोध का नन्हा सुर

बेचारे फूल और पौधों के पास अपने हितों की रक्षा का कोई जरिया नहीं है. सो उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के 75 साल पुराने बगीचे को तबाह करके उस पर अतिविशिष्ट लोगों के लिए एक गेस्ट हाउस खड़ा करने की योजना बना डाली. गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री वीरबहादुर सिंह ने 5 करोड़ रुपए की लागत वाले इस गेस्ट हाउस की नींव का पत्थर भी धर दिया.

बगीचे के समूल नाश के फैसले पर हफ्तों तक तो लोगों की निगाह ही नहीं गई पर अब जाकर विरोध का एक नन्हा सुर उठा है—स्थानीय कान्वेंट की कक्षा आठ में पढ़ने वाली अपराजिता गुप्ता के रूप में. उसने प्रधानमंत्री राजीव गांधी को चिट्ठी लिखी, "किसी पौधे को काटना किसी बच्चे के कत्ल की तरह है क्योंकि पौधों में भी

प्रदीप शाह

बगीचे में नींव का पत्थर: हरियाली की कुर्बानी

बच्चों की ही तरह जान होती है." तीन एकड़ में फैले इस बगीचे में सैंकड़ों पुराने पेड़ों के अलावा फूल पौधों की हजार से ज्यादा किस्में हैं. यह बच्ची अब अपने मिशन में कामयाब हो या नहीं पर उसकी आवाज ने बहुत से लोगों के दिलो-दिमाग को झकझोर दिया है.

महाजनों के रास्ते पर

लगता है केंद्रीय मंत्री मोतीलाल वोरा और केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्रालय एक-दूजे के लिए ही बने हैं. फिलहाल वोरा के पास इस मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार है. मध्यप्रदेश में मुख्य मंत्री के तौर पर अपने तीन साल के कार्यकाल के दौरान दिल्ली से आई राजनैतिक हस्तियों को वे उदारता से राज्य का हवाई जहाज मुहैया कराते रहे. खुद भी सरकारी जहाज का भरपूर इस्तेमाल किया.

केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य और परिवार कल्याणमंत्री के बतौर

वोरा: उड़नप्रेमी

शामिल किए जाने के बाद पिछले पखवाड़े वे पहली बार भोपाल गए और अपने प्रदेश के लिए कई नई उड़ानों की घोषणा कर डाली. उन्होंने एलान किया कि प्रदेश में वायुदूत सेवाओं का जाल बिछाया जाएगा और इसका आधार होगा भोपाल हवाई अड्डा.

यूं तो वोरा 'महाजनों येन गता: स पंथा' वाली कहावत ही चरितार्थ कर रहे हैं रेल राज्य मंत्री माधव राव सिंधिया ने अपने शहर ग्वालियर को एक बड़े रेलवे परिसर में पहले ही तब्दील कर दिया है. अर्जुन सिंह भी जब केंद्रीय संचारमंत्री थे तो उन्होंने नए टेलीफोन देने में कायदे कानून ताक पर रख दिए थे.

वामपंथी ख्याली पुलाव

मार्क्सवादी, इंका से भी ज्यादा भाजपा से चिढ़ते हैं. इसलिए कुछ हफ्ते पहले माकपा नेता ई.एम.एस. नंबूदिरीपाद ने जब केरल में विश्वनाथ प्रताप सिंह और जनमोर्चा के दूसरे नेताओं का स्वागत किया तो उसे सही ठहराते हुए कहा कि जनमोर्चा नेता ने आखिरकार भाजपा से रिश्ते तोड़ने का फैसला कर लिया है. अब सोचिए कि मार्क्सवादी उस समय कितने खीजे होंगे जब चंद दिनों बाद ही वी.पी. सिंह दिल्ली में हुई भाजपा-लोकदल रैली में दिखाई पड़े.

नाडर: असंतुष्ट

पर केरल की वामपंथी लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार (एलडीएफ) ज्यादा परेशान है. विधानसभा में लोकदल के इकलौते सदस्य और राज्य के खेलमंत्री नीललोहित दास नाडर के व्यवहार से. नाडार एक तो दिल्ली की रैली में शामिल हुए, ऊपर से शुद्ध हिंदी में भाषण भी दे डाला. माकपा ने इसके लिए उनकी काफी खिंचाई की.

एलडीएफ तालमेल समिति के संयोजक और माकपा के दिग्गज एम.एम. लारेंस ने नाडर से सफाई मांगी. नाडर का जवाब था, "रैली में भाषण देकर मैंने कोई पाप नहीं किया. हम सबका एक ही मकसद है—इंका कुशासन की मुखालफत करना."

शुद्ध गांधीवादी तरीका

पिछले महीने इंका ने जब गुजरात में महात्मा गांधी के दांडी मार्च को एक बार फिर ताजा किया (देखिए आजकल) तो कम-से-कम एक मामले में तो इतिहास दोहराया ही गया. 58 साल पहले स्वतंत्रता सेनानियों को इसके लिए ब्रिटिश सरकार की लाठियां खानी पड़ी थीं तो इस बार लाठियां बरसी केंद्रीय मंत्रियों—पी. शिवशंकर और चिंतामणि पाणिग्रही पर. 11 किलोमीटर के मार्च की अगुआई करते हुए राजीव गांधी लगभग दौड़

प्रभात पटियार

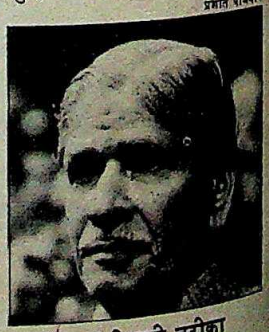

शिवशंकर (बाएं) और पाणिग्रही: गांधीवादी तरीका

ही रहे थे. दोनों मंत्रियों ने जब राजीव के पास पहुंचने की कोशिश की तो पुलिस वालों ने उन्हें रोक लिया. वे पुलिस वालों से उलझ गए, इससे पहले कि मंत्री अपनी पहचान बता पाते उन पर लाठियां बरसने लगीं. पर दोनों ने माहौल के मुताबिक 'गांधीवादी रास्ता' अपनाया और कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं करवाई. फिर भी हंगामा हो गया. सो राज्य सरकार ने अब इस पर जांच बिठा दी है.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

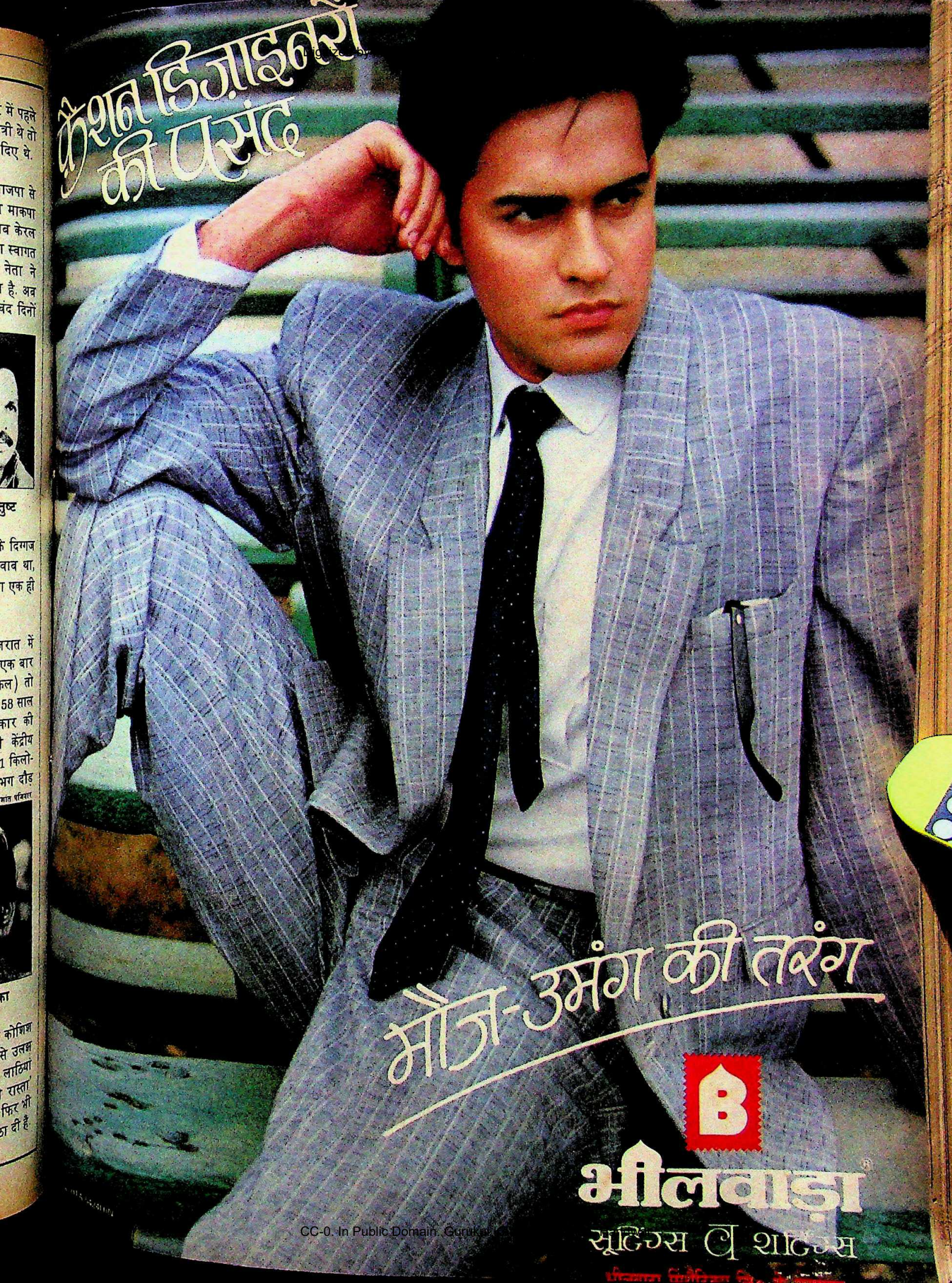

CC-0. In Public Domain. Gurukul

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सोने पे सुहागा– गोल्ड का सुर्ख़ लाल

कोडाकलर गोल्ड

चमकीला नीला, सदाबहार हरा, जगमगाता पीला, सुर्ख़ लाल. कोडाकलर गोल्ड फ़िल्म हो तो जीवन का हर रंग खिल उठे बेहतरीन, बेमिसाल. उन्नत तकनीक के फलस्वरूप रंग ऐसे निखर आयें कि हर चित्र सजीव हो जाये.

एकमात्र कोडक की तकनीक का कमाल–कोडाकलर गोल्ड फ़िल्म.

लोग जानते हैं इसका मोल– तभी इसका नाम रखा है–गोल्ड.

Kodak is colour

HTA 1899

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सवारी वही जो हमेशा सबसे आगे जाए
इंजिन ऑइल वही
जो दुनिया में सर्वोत्तम कहलाए.

गल्फ प्राइड 2-T इंजिन ऑइल. सभी टू-स्ट्रोक इंजिनों वाले स्कूटर, मोटर सायकल, मोपेड के लिए पेट्रोल में तुरंत घुल-मिल जाने वाला 2-T ऑइल. हर सावधानी से तैयार किया गया.

गल्फ प्राइड 2-T आधुनिक तकनीक वाले फार्मूले से बनाया गया है, जिससे शहर के थमते-चढ़ते ट्रैफिक में इंजिन को पूरी सुरक्षा मिले, रफ्तार आसानी से बढ़े, पिकअप में ज्यादा तेजी आए, इंजिन को ज्यादा पावर मिले और इंजिन की देखभाल का खर्च घटे.

गल्फ प्राइड 2-T ऑइल से सवारी की शान बढ़े, इंजिन की जान बढ़े. आखिर यह फर्स्ट क्लास इंजिनों के लिए तैयार फर्स्ट क्लास इंजिन ऑइल जो है.

पेट्रोसिल ऑइल कं.लि. गल्फ ऑइल इंटरनैशनल कं., यू.एस.ए. के लाइसेन्सधारक
रजिस्टर्ड ऑफिस: ३, दिनशा वाच्छा रोड, बम्बई ४०० ०२०. फोन : २२०८१८, २३२३०३. टेलेक्स : ०११-३५२०.
कॉर्पोरेट कार्यालय : नई दिल्ली • अहमदाबाद • कलकत्ता • मदास. पेट्रोसिल के डिपो डिस्ट्रीब्यूटर और स्टॉकिस्ट पूरे
देश में हैं. गल्फ ल्युब्रिकेन्ट सभी प्रमुख ऑटो स्पेयर पार्ट डीलरों के यहां भी मिलते हैं.

इंजिन हो जानदार, सवारी हो शानदार.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

THE EDGE-B/88/POC/140 HN

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अंगकोर वाट

बीते वैभव की पुनर्स्थापना

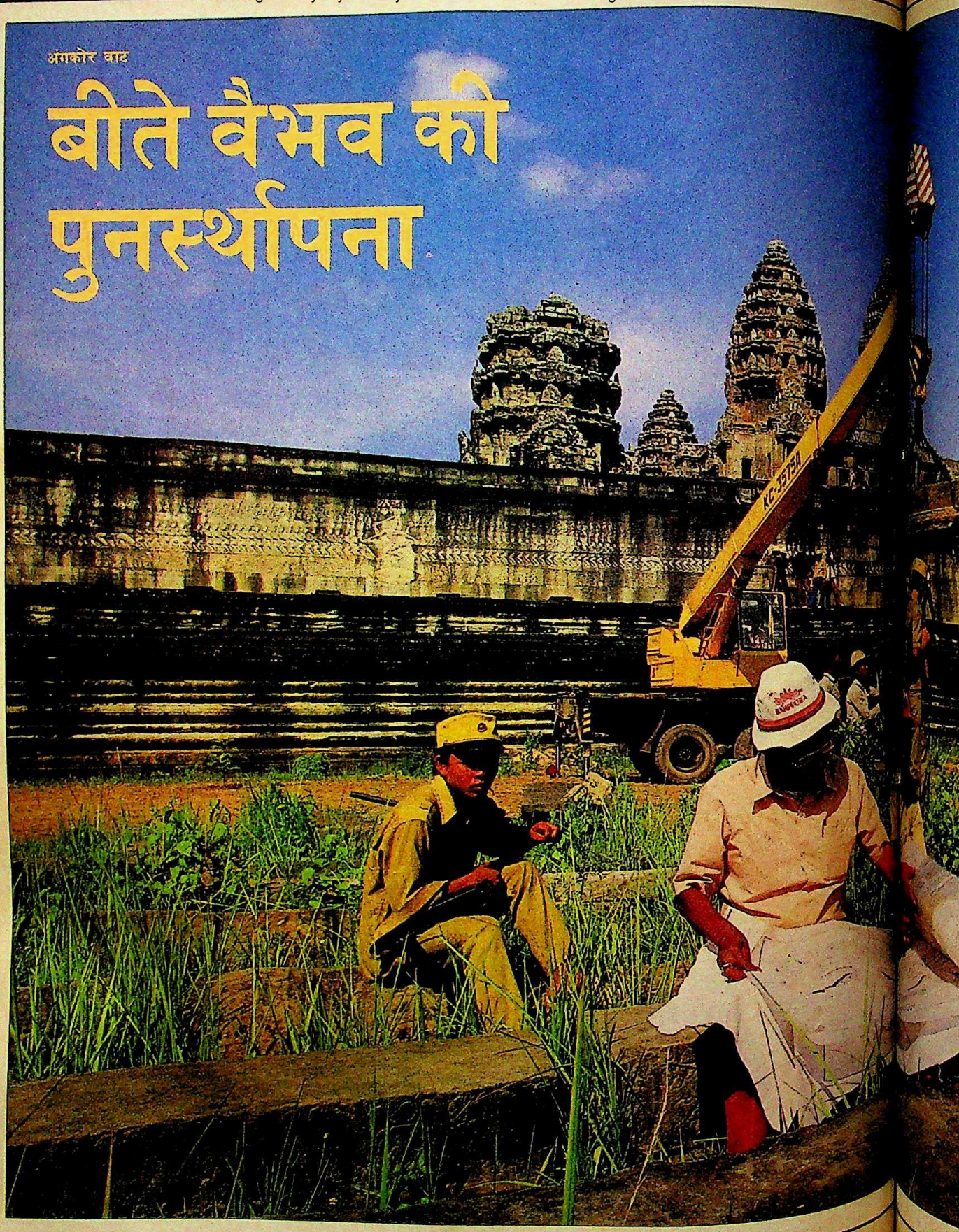

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंगकोर वाट आठ साल पहले तक रहस्य और बारूद के धुएं के साये में रहा. कंपूचिया में युद्ध जैसे-जैसे लंबा खिंचता गया, उसके घाव मंदिर पर भी दृष्टिगोचर होने लगे. उधर जंगल भी उसकी विशाल अट्टालिकाओं को अपने आगोश में लेने लगा. प्रकृति की इस विनाशकारी लीला के साये में अंगकोर वाट के बड़े-बड़े स्तंभ धंसने लगे, उसकी दुर्लभ नक्काशियां चिटकने लगीं. दुनिया के एक विशालतम स्मारक पर तबाही का भूत मंडरा रहा था.

भारत को भी इसकी चिंता थी. दो साल पहले कंपूचिया ने अंगकोर वाट की मरम्मत के लिए भारत से छह साल का एक समझौता किया. यह बेहद प्रतिष्ठाजनक पुरातात्विक जिम्मेदारी थी. अंगकोर वाट भारत के साथ उस देश के प्राचीन सांस्कृतिक संबंधों का एक जीता जागता प्रमाण है. 1986 में भारतीय पुरातत्वविज्ञानियों की एक टोली ने वहां पहुंचकर काम शुरू किया. तब से वे चुपचाप मगर तेजी से काम कर रहे हैं. अगर कोई वहां जाना चाहे तो उसे सिर्फ तीन घंटे ही उस इलाके में गुजारने की इजाजत है. मगर पिछले पखवाड़े कंपूचिया सरकार ने 'इंडिया टुडे' के छायाकार प्रणात पंजियार और प्रमुख संवाददाता राज चेंगप्पा को अंगकोर वाट और इर्दगिर्द के मंदिरों में चार दिन रहने की अनुमति दी. चेंगप्पा की रिपोर्ट:

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सीधे-सादे कहा जाए तो अंगकोर वाट पत्थर का ही कमाल है. यहां हिंदू प्रतीकात्मक कला चरम पर पहुंची दिखती है.

इसके निर्माताओं के इरादे भी बड़े ही थे. इतने बड़े कि इसके चारों ओर खाई का चक्कर काटने में तीन घंटे लगते हैं. और खाई इतनी चौड़ी जितना हरिद्वार में गंगा का पाट है. इसका भीतरी आंगन भी फुटबाल के दो स्टेडियमों के बराबर है. यहां के पांच मुख्य बुर्ज तो लंबाई में कुतुब मीनार जितने हैं.

फिर भी मंदिर की 50,000 टन शिलाएं इसके भीमकाय अग्रभाग पर हल्के से टिकी हुई हैं. खुली छत पर गैलरियां ऐसे फैली हुई हैं मानो कोई विशालकाय आदियुगीन पक्षी उड़ान भरने की तैयारी में हो. कई मेहराबी छतों की चोटी पर बने पांच शंखाकार बुर्ज आकाश को छूते प्रतीत होते हैं. कुल मिलाकर यहां एक तिलस्मी माहौल है, धार्मिक सृष्टि की एक ऐसी रचना है जिसे इसके निर्माता और 12वीं सदी के खमेर महाराजा सूर्यवर्मन (द्वितीय) ने रचने का प्रयास किया था.

उन्होंने सूक्ष्म रचनाओं की भी अनदेखी नहीं की है. हरेक स्तंभ पर हिंदुओं के पौराणिक देवी-देवताओं के चित्र खुदे हुए हैं जिन्हें पाप के विरुद्ध पुण्य के अनादि संघर्ष में लीन दिखाया गया है. गैलरियों में लगी आधार पटल से उभरती हुई नक्काशीदार आकृतियां न सिर्फ दुनिया में सबसे लंबी हैं बल्कि उन्हें शायद बेहद नजाकत से तराशा भी गया है. सोने में सुहागा तो वे हजारों विषयासक्त अप्सराएं हैं जो अलौकिक शान से

विशाल मंदिर के इर्दगिर्द बनी खाई का चक्कर काटने में तीन घंटे लगते हैं

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मंदिर की दीवारों की शोभा बढ़ा रही हैं.

अंगकोर वाट की वास्तुकला पर खासकर हमेर छाप है तो इसके पीछे प्रेरणा निश्चय ही भारतीय है. मंदिर के निर्माता ने अपने विशेष आराध्य विष्णु को शिलाओं के इस स्मारक में चिरस्मरणीय बना दिया है.

अब करीब 800 साल बाद भारतीय फिर यहां पर हैं. समुद्री व्यापारी या भगवा-धारी प्रचारक के रूप में नहीं बल्कि इस बार वे मंदिर की पुनर्स्थापना करने आए हैं. उनका काम ऐतिहासिक मिशन से कम नहीं. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की इस टीम के सामने बेहद चुनौती भरा काम इस कल्पनातीत स्मारक की मौलिक तेजस्विता लौटाना है.

युद्ध से तंग आ चुके कंपूचियावासियों के लिए 'वाट' (जिसका मतलब है मठ बन चुकी राजधानी) महज एक प्रतीक नहीं बल्कि, संस्कृतिमंत्री चेंग फॉन के मुताबिक, "यह राष्ट्र की आत्मा है." वे नाटकीय अंदाज में कहते हैं, "अंगकोर वाट की पुनर्स्थापना करके भारतीय टीम दरअसल एक तरह से हमारी आत्मा पर ही मरहम लगा रही है."

उधर भारतीय टीम के लिए, उसके नेता कल्याणप्रिय गुप्त के अनुसार, "यह एक तरह की घर वापसी है." पहली बार यहां आने पर उनकी नजर अंगकोर वाट के भव्य पश्चिमी द्वार पर शैय्या पर लेटे विष्णु की नाभि से निकलती ब्रह्मा की आकृति पर पड़ी. दहलीज पार करते ही उन्हें मंदिर के विस्मयकारी भवन को देखकर आश्चर्य भी हुआ और निराशा भी. वे कहते हैं, "मैं तो उसका इतना बड़ा आकार और सुंदरता देखकर दंग रह गया. भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है पर इतना मैं जानता था कि इस भव्य मंदिर को बचा पाना कोई आसान काम नहीं."

हर कहीं बर्बादी के निशान दिखते थे. संबुल की बेलों ने खाई पर हरे रंग की एक मोटी तह जमा दी थी. आंगन उजाड़ जंगलों सरीखे हो गए थे. शैवाल और काई से उसकी भव्य अट्टालिकाएं स्याह पड़ गई थीं. पूरी इमारत को थामने वाले स्तंभ चरमराने लगे थे. आधार-पटल से निकलती गैलरियों में बड़ी-बड़ी दरारें आ गई थीं और जगह-जगह पर की गई नक्काशी उखड़ रही थी. अति-सुंदर अप्सराओं का तो और भी बुरा हाल था. भद्दे-से हरे-हरे धब्बों ने उनकी सुंदरता को बट्टा लगा दिया था.

युद्ध की कुछ कीमत भी इसे चुकानी पड़ी अंगकोर वाट की कुछ सर्वोत्तम नक्काशीदार कलाकृतियां गोलियों से बिंध गईं. एक द्वार-

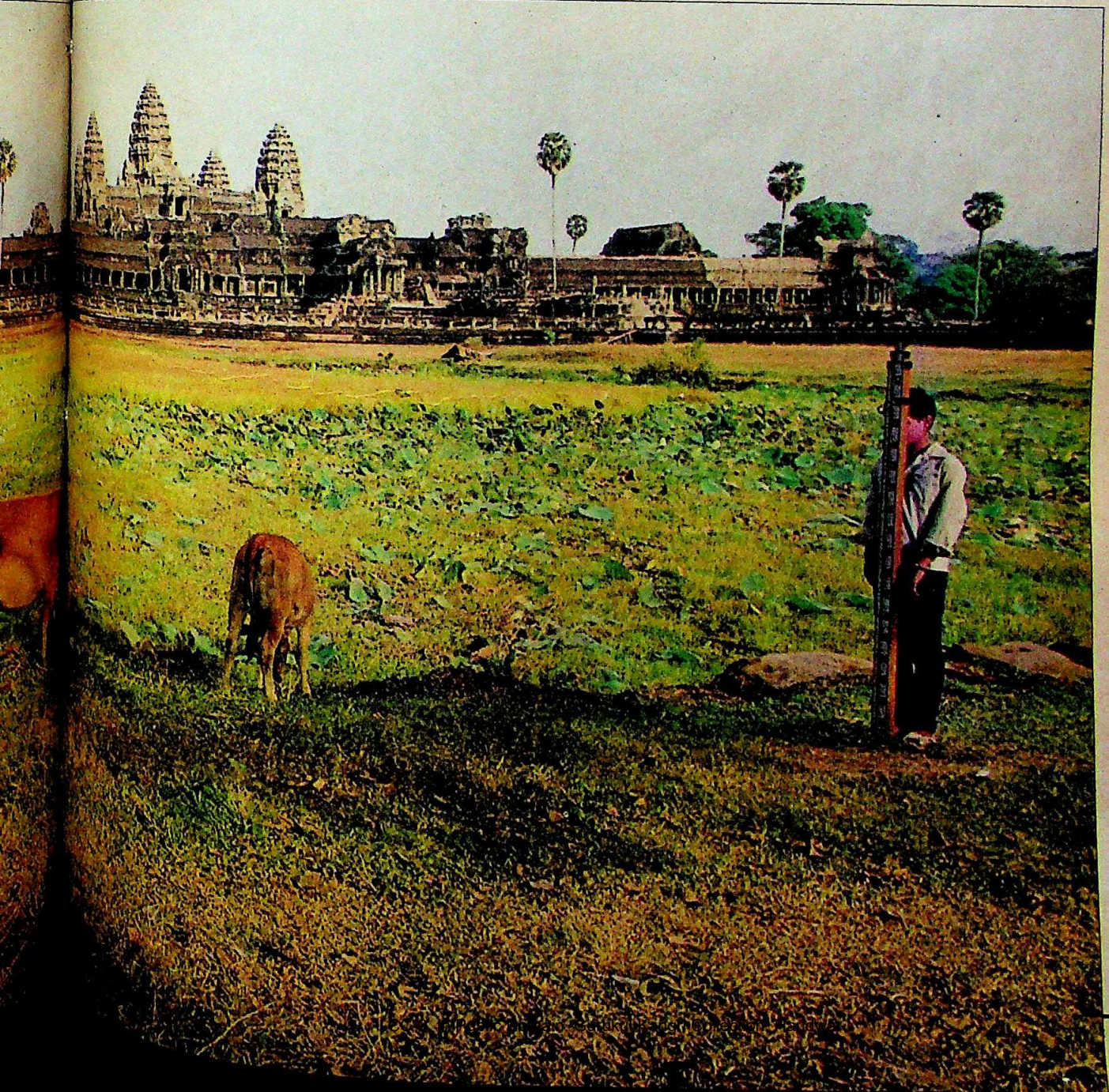

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"अपने डॉक्टर से यह जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि केयो-कार्पिन हेयर वाइटालाइज़र से सचमुच बालों का झड़ना रुक जाता है।

लेकिन मुझे विश्वास तब हुआ जब मैंने इसका इस्तेमाल किया।"

''मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया कि केयो-कार्पिन हेयर वाइटालाइज़र*, व्यापक गवेषणा पर आधारित एक अपूर्व वैज्ञानिक फार्मूले से बना है। उन्होंने यह भी बताया कि यह बालों की जड़ों को मज़बूत करनेवाले सभी आवश्यक प्रोटीन तत्व, को-एन्जाइम और विटामिन भी उपलब्ध करता है।

मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि इसने मेरे बालों का झड़ना निश्चितरूप से रोक दिया है और साथ ही रूसी भी खत्म हो गई है।''

देखिए, गवेषणा-रिपोर्ट से उद्धृत एक अंश:

''सभी मामलों में रूसी के सम्पूर्ण खात्मे के साथ ६६.६६% मामलों में शानदार एवं ३३.३३%में बढ़िया नतीजा हासिल हुआ और बालों का झड़ना तो लगभग शत प्रतिशत रुक गया...इसलिए, यह कहा जा सकता है कि केयो-कार्पिन हेयर वाइटालाइज़र की सफलता-दर शत प्रतिशत है।''

इंडियन मेडिकल गज़ट ११८ २२३ (१९८४)

बालों का झड़ना रोकने का प्रमाणित वैज्ञानिक तरीका।

Dey's® दे'ज मेडिकल की संभाल, आपका भरोसा।

*यह शृंगार सामग्री नहीं है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सलोरा-क्वॉलिटी की ऐसी बुलन्दी, औरों का अरमान.

सलोरा टीवी–टेलिवीजन निर्माण के हर कदम पर उत्कृष्टता को ही कसौटी माननेवाली कंपनी ईसीपीएल की देन.

क्षेत्रीय सहयोग : संसार की अग्रणी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों से–डिफ्लेक्शन कम्पोनेन्ट और स्पीकर के लिए जापान की नैशनल और फॅास्टर कंपनियों से; मॉनिटर और कम्प्यूटर के लिए फ्रांस की थॉम्पसन एसए जैसी कंपनियों से तकनीकी सहयोग, जिससे ईसीपीएल के हर टीवी ने पाई उत्कृष्टता व कार्यकुशलता.

सर्वोत्तम तकनीक : ईसीपीएल द्वारा स्थापित असोशिएटेड इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च फाउंडेशन (AERF) एक प्रमुख अनुसंधान-विकास केन्द्र है. भारत सरकार से मान्यताप्राप्त इस केन्द्र में १०० से भी अधिक वैज्ञानिक और विशेषज्ञ जुटे हुए हैं भविष्य के लिए नित नयी तकनीक के विकास में.

आधुनिकतम सुविधाएं : ईसीपीएल के सभी सातों कारखानों में ऑटोमेटिक कम्पोनेन्ट इन्सर्शन और वेव सोल्डरिंग जैसी आधुनिकतम मशीनें लगी हैं ताकि आधुनिक से आधुनिक टीवी बन सकें. ईसीपीएल के टीवी विदेशों में तो निर्यात होते ही हैं, भारत में भी ये इतने लोकप्रिय हैं कि १९८६ में १,८०,००० और १९८७ में २,२५,६०० से भी अधिक कलर और ब्लैक एण्ड व्हाइट टीवी बनाये गये. इस लोकप्रियता के पीछे है देश के कोने-कोने में उपलब्ध त्वरित सर्विस.

सलोरा टीवी के निर्माता है ईसीपीएल–एक उत्कृष्ट उत्पादनकर्ता.

कलर और ब्लैक एण्ड व्हाइट टीवी

ECIL

सलोरा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

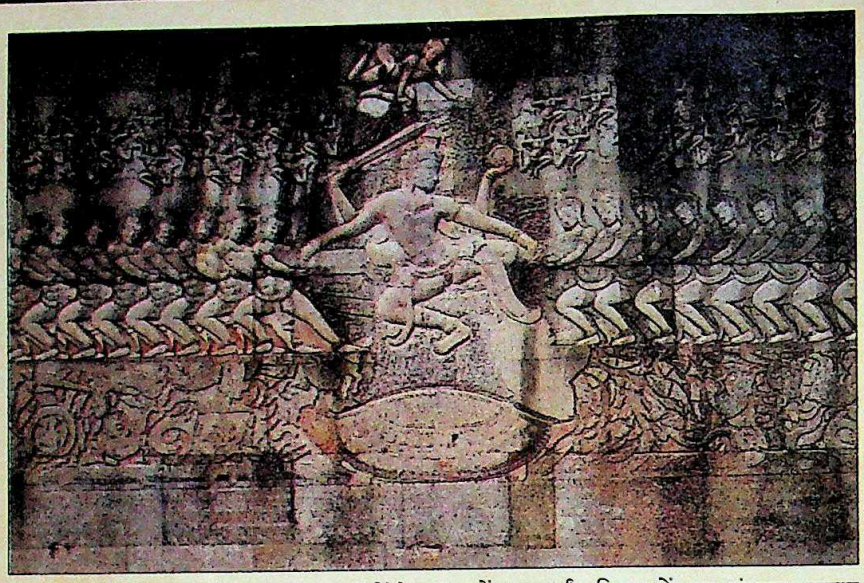

मंडप तो गोले से उड़ ही गया. नापाम बमों ने पत्थर के अनेक जंगले तबाह कर दिए. और एक उन्मादी प्रकोप में तो बुद्ध की 50 प्रतिमाओं के सिर ही उखाड़ दिए गए. (15वीं सदी में अंगकोर वाट बौद्ध मठ में बदल दिया गया था.) सबसे ज्यादा नुकसान तो लगातार बारिश से हुआ.

आज पुनर्स्थापना करने वाले भारतीय बिलकुल नए अवतार के रूप में वर्षा के पानी से जूझ रहे हैं. पश्चिमी गैलरी के असीम बरामदे में भवन—निर्माण इंजीनियर एम.एम. कानाडे घुटनों के बल बैठे त्रुटियों की जांच कर रहे हैं. वे गैलरी का एक रेखाचित्र निकालकर अंगकोर वाट की मूल त्रुटि बताते हैं (देखें रेखाचित्र). खाई से निकाली गई बालू के एक टीले पर इसकी नींव रखी गई. फर्श के लिए उन लोगों ने एक-एक फुट ऊंचे लेटराइट (सख्त मिट्टी) के टुकड़े बिछाए और उन पर बलुआ पत्थर की बड़ी-बड़ी शिलाएं रख दीं. टोडेदार छत के नीचे उन्होंने दो पंक्तियों में स्तंभ बना दिए और उन्हें कड़ियों से जोड़ दिया. पर लगता है जल्द-बाजी में (अंगकोर वाट का निर्माण 37 साल में पूरा हुआ) उन्होंने पत्थर के बजाय लेटराइट पर ही अंदरूनी स्तंभ खड़े कर दिए.

वक्त बीतने के साथ-साथ बरसात के पानी ने इसके लेटराइट आधार को खिसका दिया जिससे बहुत-सी जगहों पर जमीन धसक गई. बाहर के पथरीले स्तंभ मजबूती से खड़े रहे पर अंदर वाले स्तंभ टेढ़े होने लगे और कानाडे के मुताबिक, "झटके मारने लगे." इस खींचातानी से उन्हें जोड़ रही कड़ियों में भारी दरारें आ गई. शिलाओं का संतुलन इतना नाजुक है कि यदि एक स्तंभ गिरता है तो उससे पूरी इमारत पर असर पड़ता है. इमारत को खड़ा रखने वाले ज्यादातर स्तंभों के साथ ऐसा बार-बार हुआ है.

यूनानी वास्तुकला से बने मंदिर के बरामदों में सीलन भर गई है और वे दुर्गंध छोड़ने लगे हैं. क्या यहां से पानी रिसता है? "नहीं, ये तो चमगादड़ों के बीट हैं," गुप्त बताते हैं. हजारों चमगादड़ मंदिर में डेरा डाले हुए हैं. उनकी बीट से बलुआ पत्थर गलकर इमारत को नुकसान पहुंचाता है.

बाहर एक और भारतीय इंजीनियर डी.टी. कर्मचांदी मंदिर के दूसरे दुश्मन का परिचय दे रहे हैं. यह पथरीली शिला से झांकता एक नन्हा-सा पौधा है. शिला को खिसकाने के लिए आठ खमेर मजदूरों की दरकार है. इस पौधे की कलाई जितनी मोटी जड़ें हैं जो नीचे दूर तक भयानक जबड़ों जैसी फैली हुई हैं. यह खतरनाक पौधा शायद

जगह-जगह झाड़-झंखाड़ उग आना इसकी तबाही का बड़ा कारण है

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

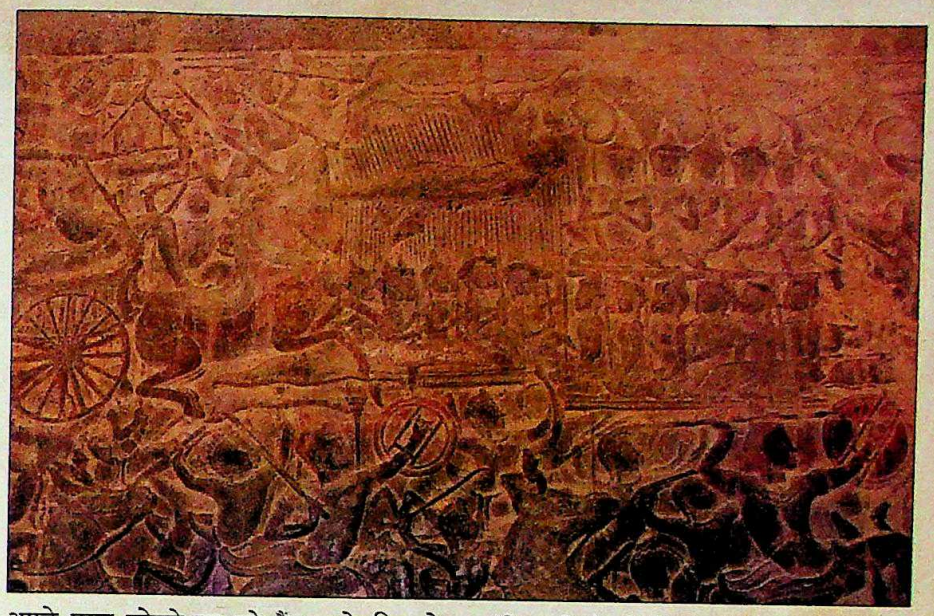

मंदिर की गैलरियों में खुदी मशहूर कृतियां पानी के रिसाव और शैवाल से खराब हो रही हैं (बाएं से) विष्णु, खंडित अप्सराएं और बाणों की शय्या पर भीष्म पितामह

कृतिया का सबसे बड़ा भारोत्तोलक है. इसने संरचना की शिला को भी खिसका दिया है. पर अंगकोर वाट की आधार पटल से निकलती भव्य गैलरियों को इससे भी गंभीर खतरे का सामना है. गैलरियों पर हुई महीन कढ़ाई हिंदुओं के लिए वास्तव में दुर्लभ कलाकृति है. 48 मीटर लंबे एक चित्रफलक पर महाभारत के दृश्य तराशे गए हैं. वह प्रसिद्ध दृश्य भी है जिसमें शोकग्रस्त शिष्यों से घिरे भीष्म पितामह बाणों की शय्या पर अपने प्राण छोड़ने जा रहे हैं. उनके सिर के चहुं ओर शैवाल उग आई है. चीटियों ने उनके जिस्म पर बांबियां खोद रखी हैं.

आगे एक नाटकीय मुद्रा में अर्जुन दिखते हैं—रथ पर सवार और तीर-कमान से लैस होकर आक्रमण के लिए तैयार. नीचे हाथ में चाबुक लिए कृष्ण हैं जो उन्हें कुछ उपदेश दे रहे हैं. ये आकृतियां पानी के रिसाव से टूटकर चूर-चूर भी हो सकती हैं.

महाभारत के चित्रफलक की दूसरी ओर 93 मीटर लंबा नक्काशीदार आधार पटल है जिस पर मंदिर के निर्माता सूर्यवर्मन (द्वितीय) की विजययात्रा दर्शाई गई है. पर लुटेरों ने इसका भी बुरा हाल कर रखा है. आधार-पटलों के पीछे छिपे सोने की तलाश में कई जगहों से उन्होंने शिलाएं तोड़ दी हैं.

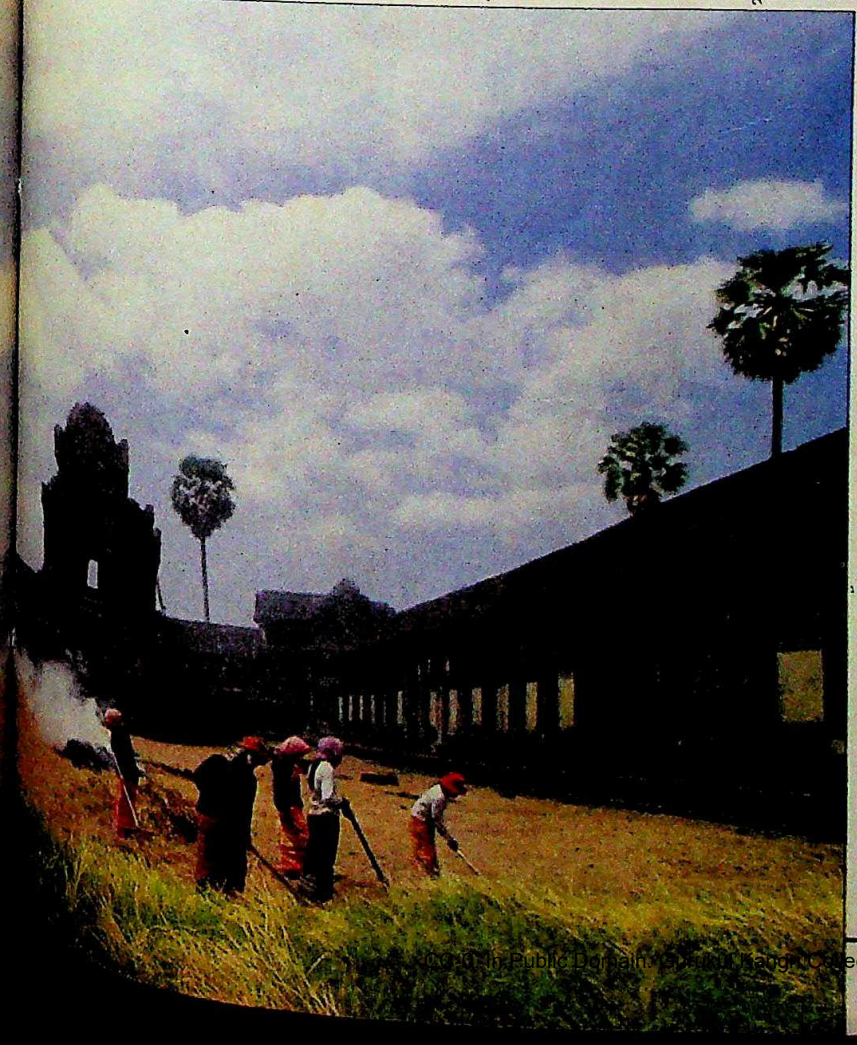

इसके आगे स्वर्ग-नरक के दृश्य हैं. यहीं हिंदू देवता यम अपना विकराल न्याय करते हैं. इनमें शायद मौजूदा कंपूचिया का ही नक्शा पेश किया गया है. शैवाल और बारिश ने स्वर्ग के दृश्यों को मिटा दिया है, सिर्फ नरक के दृश्य बचे रह गए हैं. यहां दानव व्यभिचारिनों की आंखें निकाल लेते हैं, उनके जिस्म में कीलें ठोंकते हैं और लोगों से पाप मनवाने के लिए कोड़े बरसाते हैं. दृश्य वैसा ही है जैसे पूर्व राष्ट्रपति पोल पॉट के शासनकाल में कंपूचियाई लोगों के कत्लेआम के दौरान पेश आया था.

ज्यादातर मूर्तियों को एक खास प्रकार का 'त्वचा रोग' हो गया है. टीम के रासायनिक विशेषज्ञ आर. वीरराघवन कलछी से कुछ शैवाल खुरचते हुए बताते हैं, "मासूम से दिखते सूक्ष्म जीव मंदिर की ज्यादातर बर्बादी के जिम्मेदार हैं." ये रंग-बिरंगे जीव बरसात के मौसम में दीवारों, छतों और यहां तक कि मूर्तियों पर भी तेजी से बढ़ते जाते हैं. मगर शैवाल तो अंदर तक नुकसान पहुंचाता है. इसकी जड़ों से तेजाब निकलता है जो बलुआ पत्थर को खा जाता है और उसके रासायनिक श्लेषण को तोड़ डालता है. नतीजतन दीवारें

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

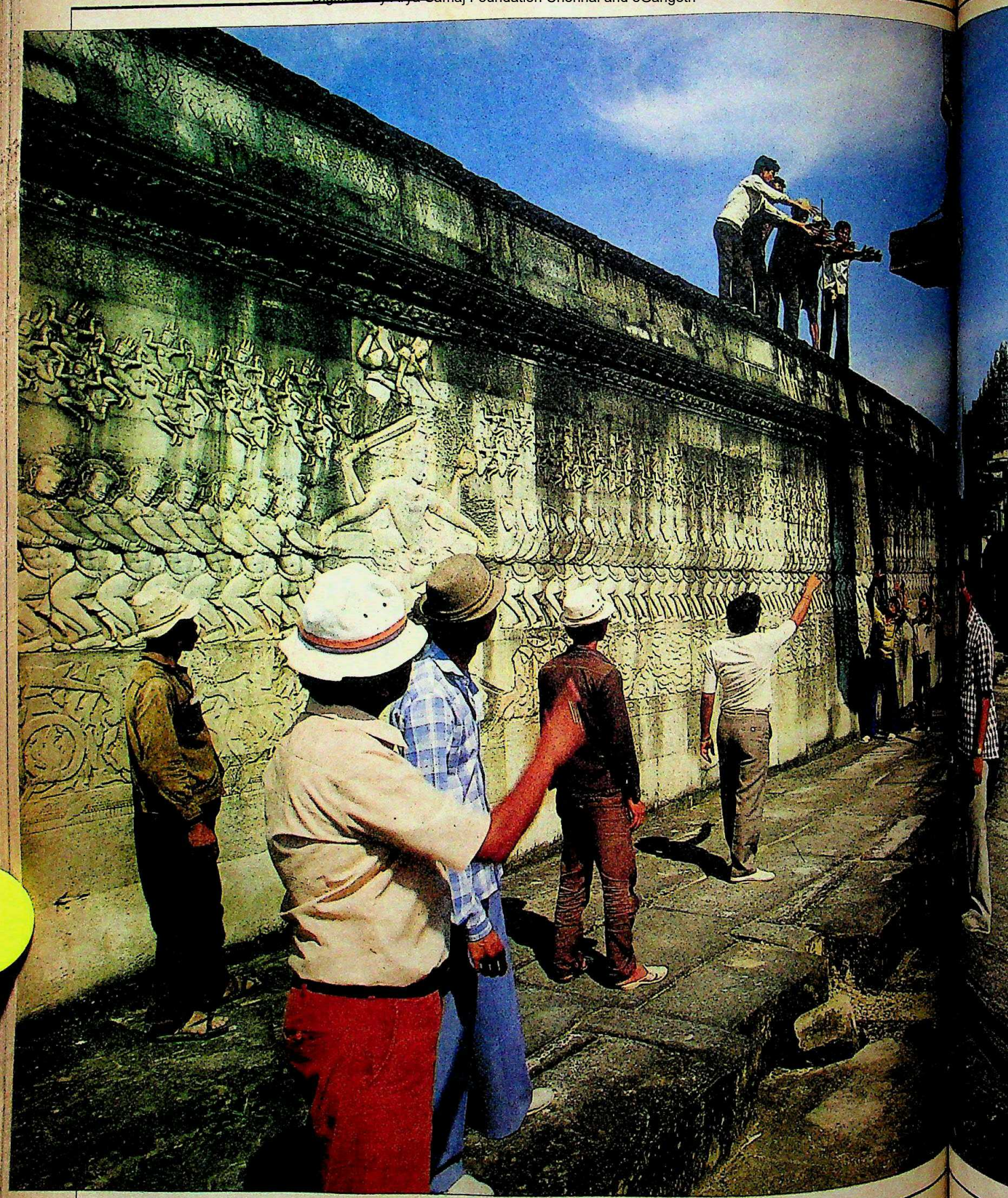

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

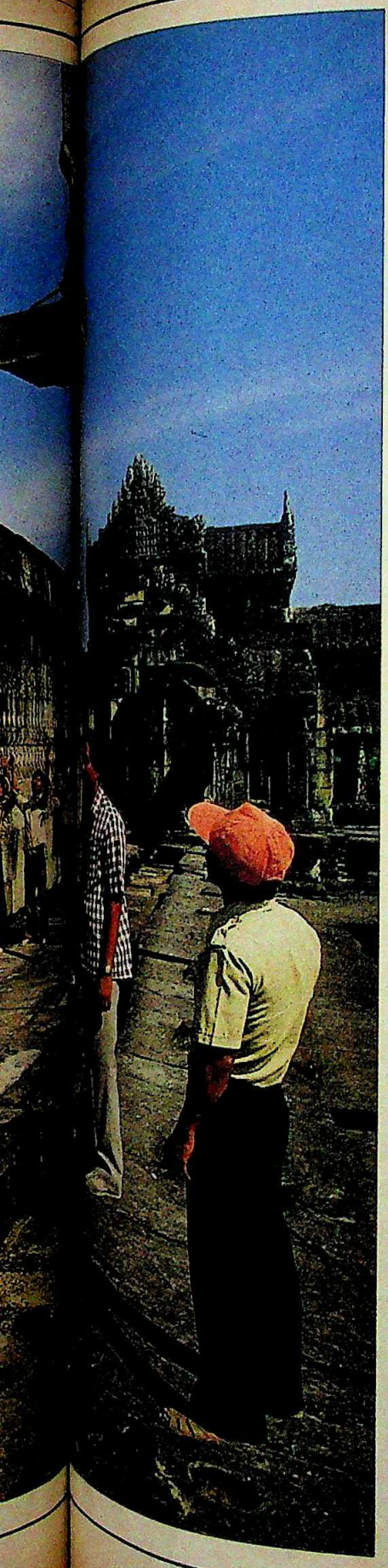

उखड़कर गिरने लगती हैं.

अचानक गोली की आवाज से निस्तब्धता भंग हो जाती है. वीरराघवन शांति से कहते हैं, "ये शिकार खेल रहे सैनिक ही होंगे." और फिर वे काम में जुट जाते हैं. गोलियों की आवाजें और स्टेनगन उठाए सैनिक उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं. मंदिर थाईलैंड की सरहद के करीब होने की वजह से कंपूचियाई सरकार को विरोधी गुरिल्लों के हमलों का अंदेशा बना रहता है. इसलिए भारतीय टीम के साथ हर समय सुरक्षा दस्ता रहता है. एक बार तो गुप्त के कमरे के पास तोप का एक गोला भी गिरा था. पर एक यह एक साल पहले की बात है. उसके बाद तो शांति ही रही.

भारतीय टीम को गोलियों की नहीं बल्कि अंगकोर वाट की पुनर्स्थापना की चिंता है. इसके पूर्व संरक्षक फ्रांसीसी भागते समय इसे अधूरा छोड़ गए थे. 1972 में यह देश छोड़ते समय वे, गुप्त के मुताबिक, 'प्राथमिक चिकित्सा' ही कर पाए थे. उन्होंने टूट रहे स्तंभों पर लोहे की खपच्चियां जड़कर ऊपर से सीमेंट लगा दिया था ताकि वे गिर न पाएं. युद्ध के दौरान जब संरक्षक दस्ते पर हमला हुआ तो उस मरम्मत का सारा रिकार्ड ही नष्ट हो गया था.

रेखाचित्र: बी.के. शर्मा

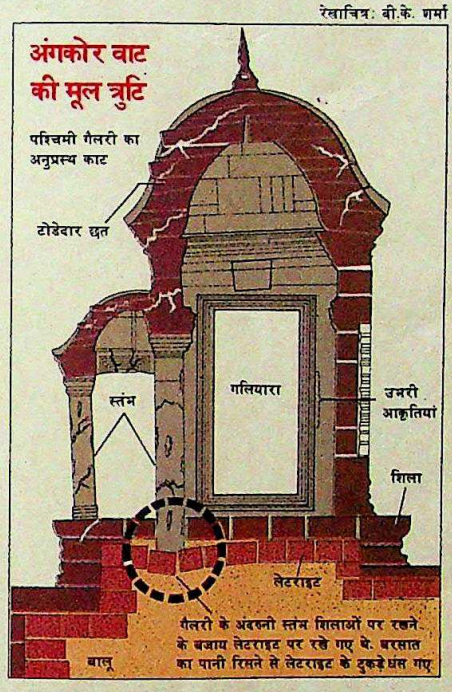

फ्रांसीसियों के तहत सहायक संरक्षक रहे पिच कियो 1980 में जब यहां लौटे तो उन्हें मंदिर की मरम्मत के लिए 20 मजदूर दिए गए. वे बरसात के बाद चप्पे-चप्पे पर उगी घास ही काट पाए.

भारत, रूस, आस्ट्रेलिया और पोलैंड समेत अनेक देशों ने सहायता की पेशकश की. लेकिन दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कोशिशों से भारत को मंदिर की पुनर्स्थापना का काम सौंपा गया. शुरू में भारतीयों को पूरे अंगकोर क्षेत्र में फैले करीब 72 मंदिरों की मरम्मत करने को कहा गया. हरेक पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत थी. पर उन्होंने यह मानकर कि अंगकोर वाट की मरम्मत में ही छह साल लग जाएंगे, खुद को इसी एक मंदिर

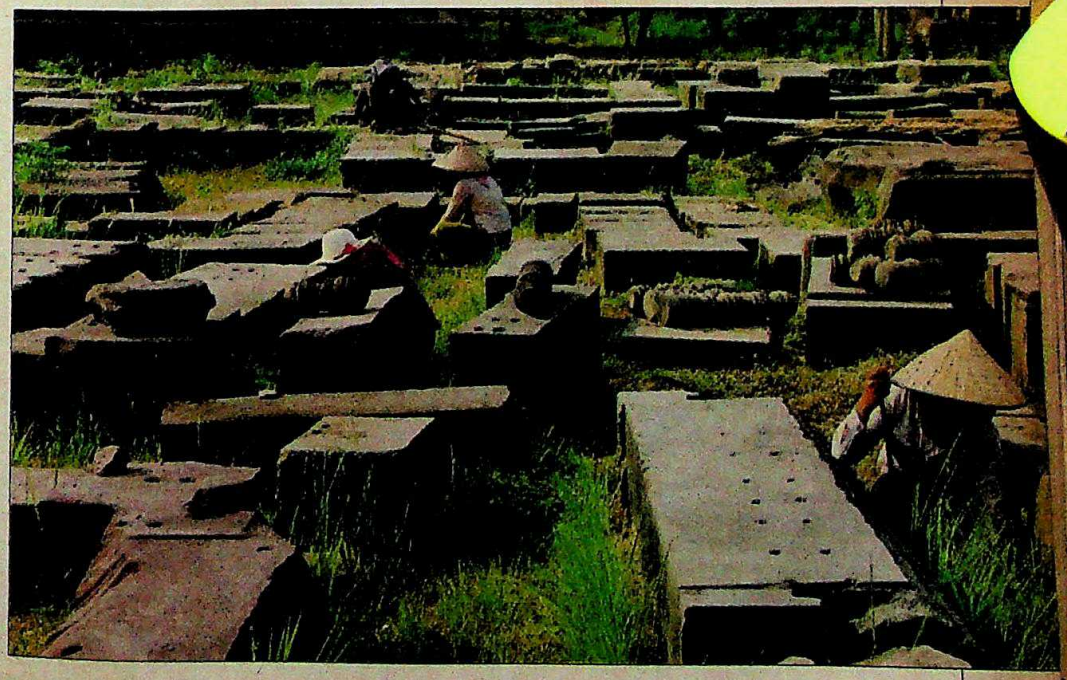

(बाएं) फ्रांसीसियों द्वारा गिराई गई गैलरी की हो रही मरम्मत और (नीचे) छत पर शिलाएं जमाने की पहेली से जूझते हुए

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

के मरम्मत के काम तक सीमित रखा.

भारत सरकार ने इस काम के लिए करीब पांच करोड़ रुपए मंजूर किए हैं. हर साल बरसात गुजरने के बाद 14 पुरातत्वविज्ञानियों की एक टीम वहां भेजी जाती है. इस टीम में भवन निर्माण इंजीनियरों और रासायनिक इंजीनियरों के अलावा एक भारतीय राजमिस्त्री भी रहता है.

दोपहर को गर्मी उतनी ही है जितनी गर्मी के मौसम में भारत में रहती है. पूर्वी गैलरी में चिंतामग्न खड़े इंजीनियर जे.जे. सूद और एस.के. जैन एक क्रेन को बड़ी-बड़ी शिलाएं उठाकर एक स्तंभ पर रखते हुए देख रहे हैं. टेढ़े स्तंभों को सीधा करने की कोशिश में फ्रांसीसियों ने पूरी गैलरी को गिरा दिया था. पर वे काम अधूरा ही छोड़ गए थे. ऐसे कामकाज भी नष्ट हो चुके हैं जिनमें शिलाओं पर लगे निशानात का जिक्र था.

काम बड़ा धीमा और उबाऊ होने की वजह से सूद और जैन जल्दी ही पसीने से नहा उठते हैं. आधा स्तंभ बन जाने के बाद उन्हें पता लगा है कि एक शिला तो सूत-भर छोटी पड़ रही है. इससे इमारत पुख्ता नहीं बन पाएगी वे उस शिला को हटाने का आदेश देते हैं. इस तरह पूरे एक हफ्ते के किए-कराए पर पानी फिर जाता है.

सारी टीम मंदिर के मूल निर्माताओं के बुद्धिकौशल पर आश्चर्यचकित है. पता नहीं कैसे उन्होंने 50 किलोमीटर दूर कुलेन पहाड़ियों से इतनी बड़ी-बड़ी शिलाएं उठाकर लाई थी. उन्होंने शिलाओं को जोड़ने के लिए कोई मसाला भी इस्तेमाल नहीं किया था. स्तंभ बनाने के लिए वे दो शिलाओं में खांचे बनाकर उन्हें एक-दूसरे पर बिठाकर जोड़ देते थे. इस तरीके से उन्होंने एक-एक करके पूरी इमारत खड़ी कर दी थी.

नतीजा यह है कि अब टीम के सामने टेढ़े स्तंभों को सीधा करने और गिराई गई शिलाओं को सही जगह पर जमाने का चुनौतीपूर्ण काम है. खाई में पत्थर की सभी सीढ़ियां अपनी जगह से खिसक चुकी हैं. टीम को पहले सीढ़ियों के सहारे के लिए एक पक्की दीवार बनानी पड़ी, उनका लेटराइट आधार हटाकर सही जगह लाना पड़ा.

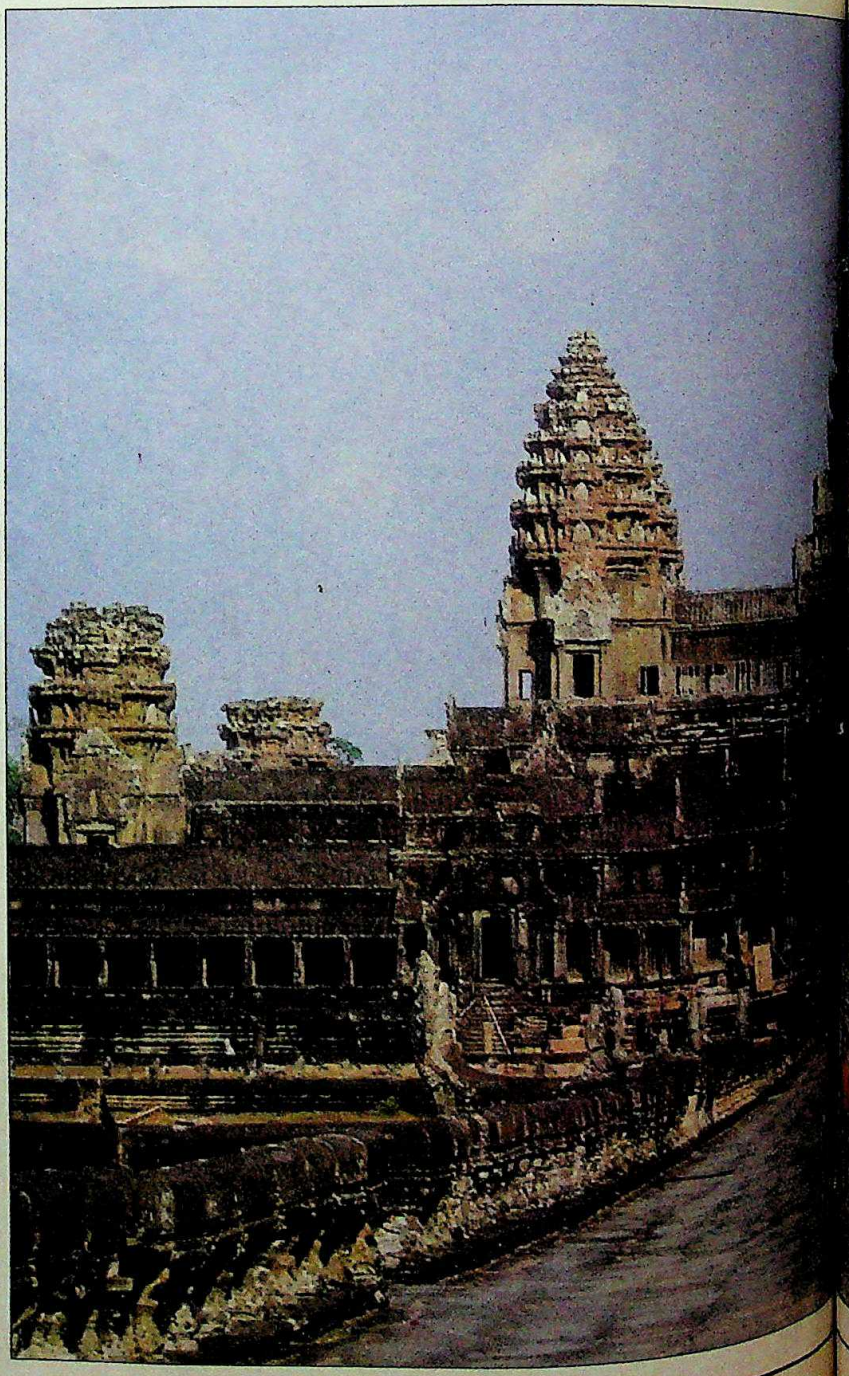

युद्ध में सिर-विहीन हुई महात्मा बुद्ध की मूर्तियों (नीचे) को जोड़ना यदि मुश्किल है तो इस पूरे प्राचीन मंदिर की पुनर्स्थापना का काम भी कम दुश्वार नहीं

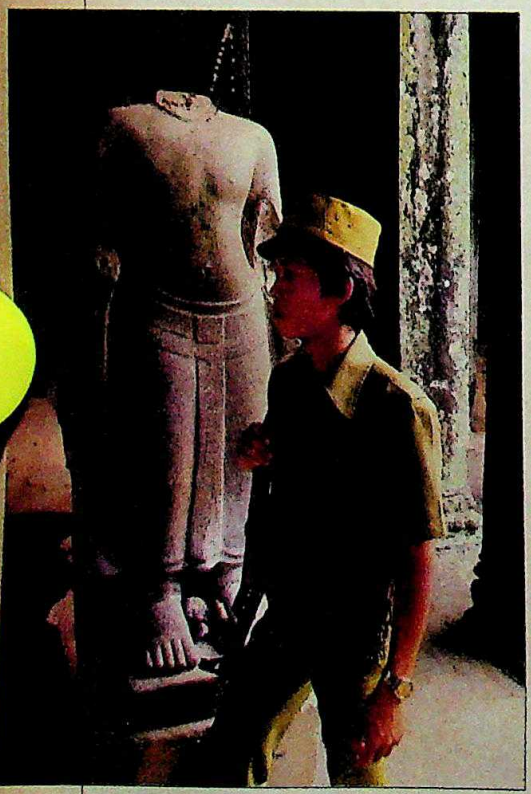

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बलुआ पत्थर न मिलने से भारतीय टीम को टूट-फूट चुके महत्वपूर्ण स्तंभ बनाने में भारी दिक्कतें पेश आ रही हैं. टीम के मॉडलर माधव शर्मा तन्मयता से काम करते दिखते हैं. एक पूरी सीढी का पत्थर का महत्वपूर्ण जंगला अपनी जगह से गायब है. शर्मा स्थानीय मजदूरों से एक जंगला तराशने को कहते हैं. इसे जानबूझकर इस तरह छीला जाता है कि वह प्राचीन लगे. फिर शर्मा रंग से भरा ब्रुश उठाकर उस पर इतने हौले से छिड़काव करते चले जाते हैं कि वह सचमुच प्राचीन लगने लगता है.

शैवाल और काई को खुरचना जितना आसान दिखता है, उतना है नहीं. नाइलोन के ब्रुश लिए करीब 50 खमेर मजदूर 20 फुट ऊंचे एक मचान पर चढ़कर किसी तनु क्षारीय घोल से दीवारों को रगड़ रहे हैं. इससे शैवाल की तेजाबी क्रिया खत्म हो जाती है. यह फिर न पनप सके, इसके लिए एक बूटीनाशक रसायन का छिड़काव किया जाता है.

पर जब पश्चिमी द्वार पर रगड़ाई के बाद उसका मूल चमकीला भूरा रंग निकल आया तो टीम एक अप्रिय विवाद में फंस गई. स्थानीय लोगों ने अंगकोर वाट को हमेशा स्याह काले रंग में ही देखा है. अब मंदिर को भूरे रंग में देखकर उन्होंने विरोध किया. गुप्त को कंपूचियाई सरकार को यह कायल करने पर जोर लगाना पड़ा कि वे 'कंपूचियाई जनता की आंखों में धूल नहीं झोंक रहे.'

यहां भारतीयों के लिए जिंदगी खासी दुश्वार है. संचार व्यवस्था खराब होने की वजह से उन्हें चिट्ठियां और अखबार दो-दो महीने बाद मिलते हैं.

अंगकोर क्षेत्र में बना अंतिम बड़ा मंदिर, बेयॉन मंदिर बेहद आकर्षक है. इसके निर्माता जयवर्मन (अष्टम) ने इसे महात्मा बुद्ध को समर्पित किया था. मंदिर में चार शीर्ष वाले 54 बुर्ज हैं जिन पर महाराजा का सौम्य, मुस्कराता चेहरा अंकित है. पर इसकी बदहाली सदमा पहुंचाने वाली है. घनी जड़ी-बूटियों ने अधिकांश बुर्जों को उखाड़ दिया है. अंजीर का भारी-भरकम पेड़ उग आने से इसका एक प्रवेश द्वार गिरने का अंदेशा है.

सौभाग्य से अंगकोर वाट का माहौल बेयॉन मंदिर जैसा भुतहा नहीं है. क्रेन की घू-घू, पत्थर टूटने की कड़कड़ाहट और दीवारें खुरचते सैकड़ों ब्रुशों की किरकिर ने उसमें अब जीवन का संचार कर दिया है. और इस सारे शोरशराबे में खमेर मजदूरों के गीत के बोल फूटते ही दीवारें संगीत से गूंज उठती हैं.

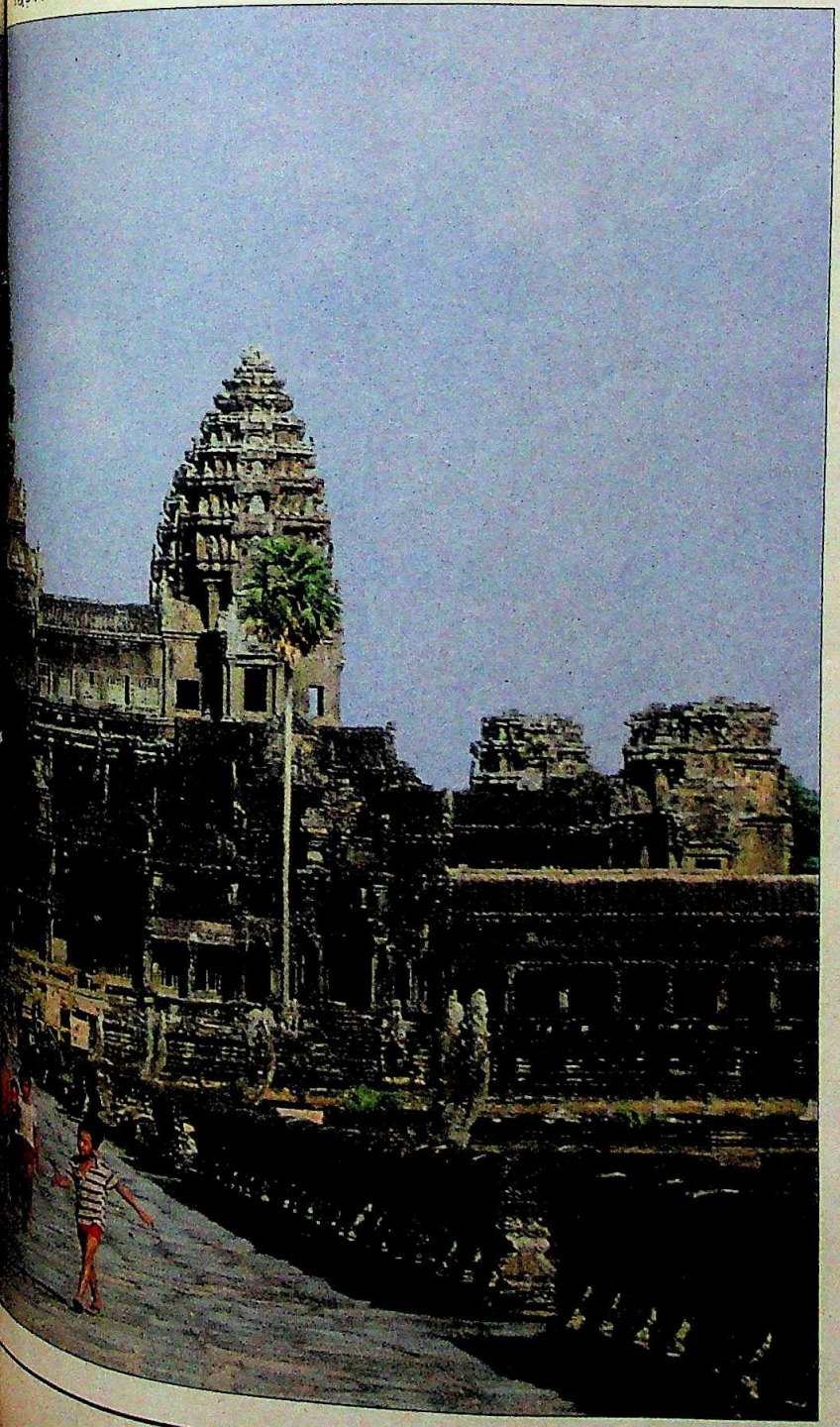

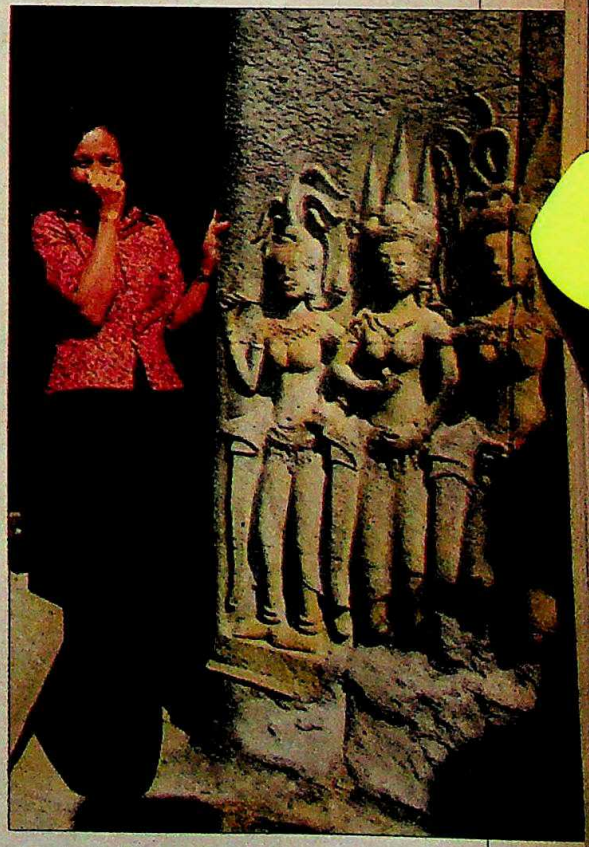

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"कुछ नवीन, कुछ अद्‌भुत... खेतान ने फिर कमाल किया"

"इसीलिये तो मैं खेतान फैन हूँ"

Hema Malini

– हेमा मालिनी

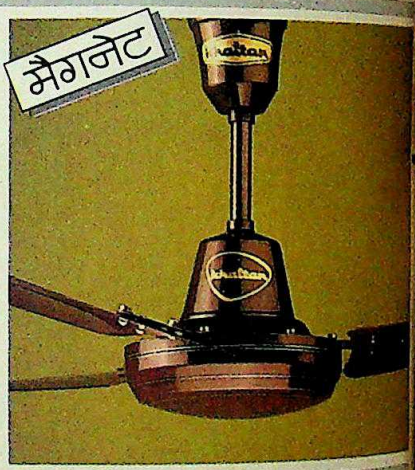

पेश हैं खेतान 3up पंखे

हर कीमत पर क्वालिटी, हर समय अनुसंधान । ये हैं खेतान की जान ! खेतान अनुसंधान केन्द्र को भारत सरकार की मान्यता का गौरव प्राप्त है । इस केन्द्र द्वारा बहुत परीक्षणों के पश्चात् एक नई शृंखला के सीलिंग पंखों का निर्माण संभव । वे हैं 'खेतान' 3 up पंखे । समुचित गुण सम्पन्न नये खेतान 3 up पंखों की ३ विशिष्टतायें इस प्रकार हैं:

1up

ज्यादा हवा
नये खेतान 3 Up पंखों में अधिक शक्तिशाली मोटर–अधिक लेमिनेशन, अधिक कापर और अधिक पोल के कारण । नतीजा: काफी ज्यादा हवा–यदि 'खेतान' को देश का सबसे हवादार पंखा कहा जाये तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं ।

2up

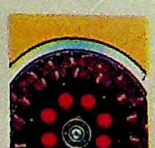

ज्यादा सक्षम... ज्यादा टिकाऊ
नये खेतान 3 Up पंखों की अनोखी कार्यकुशल मोटर । नतीजा: हर वॉट बिजली खर्च पर मिले अधिक हवा । साथ ही मोटर का तापमान कम रहने से पंखे ज्यादा टिकाऊ ।

3up

विश्वास की पराकाष्ठा

नये खेतान 3 Up पंखों की उत्कृष्टता एवम् उच्च कार्यक्षमता पर हमारा असीमित विश्वास है । नतीजा: भारत में सर्वप्रथम 'खेतान' द्वारा अनोखी की 'रिप्लेसमेंट बांड' की सुविधा अर्थात् किसी भी खेतान 3 Up उत्पादकीय त्रुटि मिलने पर पंखा मरम्मत न कर तुरंत बदलने का वादा ।

सचमुच घरेलू उपकरणों की में एक नया विस्फोट !

खेतान – सिर्फ नाम ही काफी है

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

राष्ट्रीय समुद्री उद्यान

अस्तित्व का संकट

वनस्पति की कटाई से समुद्री प्राणियों का जीवन खतरे में

पिछले साल का अभूतपूर्व सूखा एक मामले में सचमुच में अपना असर दिखा रहा है. कच्छ की खाड़ी में स्थित भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री उद्यान सूखे का प्रमुख शिकार बन सकता है. 1982 में बना यह उद्यान 162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है. इसमें समुद्री प्राणियों से परिपूर्ण 42 द्वीप हैं. लेकिन खाड़ी के समुद्री किनारे के संरक्षित गरान जंगलों में रोजाना सैकड़ों लकड़हारों और भूखे ऊंटों के आने से पार्क को जबरदस्त खतरा पैदा हो गया है.

इस उद्यान की देखरेख करने वाले राज्य वन विभाग ने यहां के लोगों को उद्यान पार्क में वनस्पतियां काटने के लिए 60,000 परमिट जारी किए हैं. ये वनस्पतियां सभी समुद्री प्राणियों का जीवन हैं. सूखे की मार को देखते हुए वन अधिकारी इन्हें वनस्पति काटने से मना करने में असमर्थ हैं. उद्यान के निदेशक जे.ए. परमार कहते हैं, "सूखा पीड़ित लोगों की तकलीफ को देखते हुए हमने उन्हें इस क्षेत्र में वनस्पति काटने की मंजूरी दे दी."

वन अधिकारियों ने सूखे को देखते हुए लोगों को इस इलाके में वनस्पति काटने की मंजूरी दी जबकि यह वनस्पति समुद्री प्राणियों का जीवन है

लेकिन इस इजाजत का फायदा लकड़ी की तस्करी करने वालों ने उठाना शुरू कर दिया. ये वनस्पतियां और लकड़ियां काटकर उनसे कोयला बनाते हैं और उसे खासा पैसा लेकर बेचते हैं. कई मछुआरे भी इस धंधे में लग गए हैं. सलाया गांव के मछुआरे रोजाना अपनी नावों से बैधर और चांक द्वीपों में जाते हैं और कम से कम 25 नावों में भरी वनस्पति लेकर लौटते हैं. फिर उसे 100 रुपया प्रति 200 किलोग्राम की दर से बेच देते हैं. राजकोट के सौराष्ट्र विश्वविद्यालय के समुद्री प्राणी विज्ञान विशेषज्ञ डॉ. आर.एम.नायक की चेतावनी है, "जिस दर से कटाई हो रही है उससे तो मई के आखिर तक पूरा जंगल ही साफ हो जाएगा. और इसके साथ ही समुद्री प्राणी भी लुप्त होने शुरू हो जाएंगे."

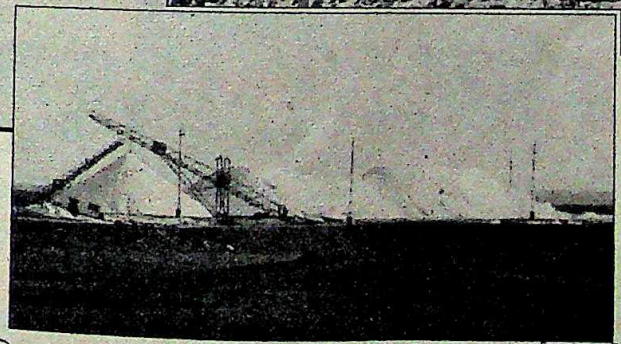

जगदीश ठक्कर

कच्छ की खाड़ी में कुछ बेहतरीन किस्म के मूंगे पाए जाते हैं. यहां कुल मिलाकर मूंगे की लगभग 40 प्रजातियां और स्पंज की 70 प्रजातियां पाई जाती हैं.

लेकिन राज्य सरकार ने समुद्री जीवन बचाने के लिए कुछ नहीं किया. उद्यान की देखभाल का जिम्मा सिर्फ 22 लोगों पर हैं जिनमें वन संरक्षक, एक सहायक संरक्षक, दो रेंज वन अधिकारी, पांच वनपाल और 14 गश्ती सिपाही हैं. खानाबदोश वनवासी मालधारी इनका काम और भी बढ़ा देते हैं.

समुद्री प्राणियों के लिए ओखा से सयाणा तक समुद्री किनारे पर फैली हुई औद्योगिक इकाइयों से भी भारी खतरा पैदा हो गया है. यहां गुजरात राज्य उर्वरक कंपनी (जीएसएफसी) के डीएपी संयंत्र और गुजरात बिजली बोर्ड के सिक्का स्थित ताप बिजली संयंत्र के अलावा नमक के 19 कारखाने हैं. इसमें कई अपना कचरा समुद्र में डालते हैं. सयाणा की जहाज मरम्मत गोदी से कचरा तेल भी पानी में बहता है.

उद्यान के निदेशक यह नुकसान रोकने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही. वन अधिकारियों का भी कहना है कि सरकार वन संरक्षण कानूनों का उल्लंघन करके कई नमक कारखानों के लाइसेंसों का नवीकरण करती आ रही है.

(ऊपर) वनस्पति काटती महिलाएं और जामनगर के पास नमक कारखाना

जीएसएफसी का खाद कारखाना और गुजरात बिजली बोर्ड का ताप बिजली संयंत्र समुद्री प्राणी विशेषज्ञों के लिए खासतौर पर चिंता का विषय बना हुआ है. विशेषज्ञों का आरोप है कि इन्हें केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के मार्ग निर्देशों की पूरी तरह नजरअंदाज कर लगाया गया. लेकिन राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि समुद्री उद्यान बनने से पहले ही इन दोनों संयंत्रों को लगाने की मंजूरी मिल गई थी.

समुद्री पानी का कई इलाकों में घुस जाना एक बड़ी समस्या बनती जा रही है. इस खतरे से निपटने में वनस्पतियों के (गरान) जंगल बहुत मददगार साबित होंगे. इसलिए राज्य सरकार को इन जंगलों के संरक्षण को वरीयता देनी होगी. नहीं तो भारत का यह पहला राष्ट्रीय समुद्री उद्यान शायद सबसे पहले बर्बाद हो जाएगा. —**उदय माहूरकर, कच्छ की खाड़ी से**

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कांग्रेस (इ)

दक्षिण पर तूफानी धावा

पर विपक्ष के मजबूत दुर्ग इतनी जल्दी नहीं ढहेंगे

इस महीने के आखिर में देश भर के 4,000 से ज्यादा कांग्रेसी जब तमिलनाडु में जमा होंगे तो दक्षिण के तीन गैर-इंका मुख्यमंत्रियों के लिए तो यह परेशानी का ही सबब होगा. करीब 32 साल में पहली बार कांग्रेस महासमिति तमिलनाडु में बैठक करेगी. पर दो दिन के इस जमावड़े का महत्व इतना ही नहीं कि इसमें इंका के मुख्यमंत्री, राज्यों के पार्टी अध्यक्ष और केंद्र व राज्य सरकारों के करीब 500 मंत्री शामिल होंगे. इसका मकसद कर्नाटक के मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े, आंध्र के नंदमूरि तारक रामराव और केरल के ई.के. नयनार पर दबाव बढ़ाना है.

यह जमावड़ा भी राजनीति की बिसात पर दक्षिण में इंका की एक चाल है. पिछले पांच साल में यह पूरा क्षेत्र पार्टी के हाथों से निकल गया है. बैठक के जरिये एक तो इंका सत्ता की पुरानी बुलंदियों पर पहुंचने का मकसद जताएगी और दूसरे उसे स्थानीय कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने में मदद मिलेगी.

वरिष्ठ संपादक ***प्रभु चावला*** *के संयोजन में बंगलूर से* ***अनीता प्रताप,*** *हैदराबाद से* ***अमरनाथ के. मेनन,*** *त्रिवेंद्रम से* ***श्रीधर पिल्लै*** *और मद्रास से* ***एस.एच. वेंकटरमनी*** *द्वारा इंका की भावी योजनाओं पर रिपोर्ट:*

राजीव गांधी की महत्वाकांक्षी योजना तो करीब छह महीने पहले ही जाहिर हो गई थी. यह सिलसिला उस समय शुरू हुआ जब उन्होंने वरिष्ठ नेताओं को एक-एक करके दक्षिण के राज्यों में बतौर पार्टी अध्यक्ष भेजा. केंद्रीय उद्योगमंत्री जे. वेंगलराव को आंध्र प्रदेश, ग्रामीण विकास राज्यमंत्री जनार्दन पुजारी को कर्नाटक और एक पूर्व इंका महासचिव को केरल में पार्टी का

कार्टून : अजीत नाइनन

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कार्यभार सौंपा गया. और फिर पिछले महीने पार्टी के वरिष्ठतम महासचिव जी.के. मूपनार को तमिलनाडु इंका का अध्यक्ष पद देकर राजीव ने यह सिलसिला पूरा कर दिया.

इन चारों को नई दिल्ली से बहुत साफ निर्देश मिले हैं कि मुख्यमंत्रियों के खिलाफ असंतोष जगाइए और पार्टी में गुटबंदी पर काबू पाइए. योजना यह है कि इन मुख्यमंत्रियों को अपने-अपने राज्य की राजधानी में ही रहने के लिए मजबूर कर दिया जाए ताकि वे दूसरे प्रदेशों की विपक्षी ताकतों से तालमेल गांठने में कामयाब न हो सकें.

इसके लिए एक समयबद्ध कार्ययोजना भी सलीकेभांति तैयार कर ली गई है:

- मुख्यमंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप बटोरे जाएं.
- जिला रैलियों में केंद्रीय मंत्री भाषण दें.
- स्थानीय शासक दलों में मतभेद पैदा करने की कोशिश की जाए.
- मुख्यमंत्री पर अंकुश लगाने और सरकार के कामों की निगरानी के लिए राज्यपालों का भरपूर इस्तेमाल किया जाए.
- दक्षिण में पार्टी के हित साधने के लिए केंद्र के पैसों का खुला इस्तेमाल किया जाए.
- सरकारी प्रचार माध्यम खासकर दूरदर्शन का इंका के पक्ष में इस्तेमाल हो.
- सबसे ऊपर राजीव हर महीने दक्षिण के कम-से-कम एक राज्य का दौरा करें.

इंका का मानना है कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में उसका मुकाबला चूंकि रामराव और हेगड़े की चमत्कारी छवि से है, इसलिए सिर्फ उनकी व्यक्तिगत साख को धूल में मिलाकर ही आगे बढ़ सकती है. उसके विरोधियों को भी यह जानकारी है. कर्नाटक जनता पार्टी के अध्यक्ष एम.पी. प्रकाश मानते हैं कि इस तरह से इंका वोटरों को बताना चाहती है कि अगर उसका दामन साफ नहीं तो दूसरी पार्टियां भी बेदाग नहीं हैं.

इसका नमूना पिछले महीने आंध्र प्रदेश में मिला जब लोकसभा सदस्य डॉ. चिंतामोहन ने रामराव पर कुनबापरस्ती को बढ़ावा देने और हरिजनों के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए संसद और अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया. इंका की शह पर उठाए इस कदम को दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया. राज्यसभा में तेलुगु देशम के नेता पी. उपेंद्र कहते हैं, "बाकायदा चुनी गई राज्य सरकारों को बदनाम करने के लिए इंका बेशर्मी से दूरदर्शन और आकाशवाणी का भरपूर इस्तेमाल कर रही है."

इंका ने सरकारी माध्यम का बेजा इस्तेमाल ही नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा काम किया है. आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से रामराव की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लगाने वाला फैसला पाने के बाद वह इस मुद्दे को राज्य की हर जनसभा में उछाल रही है.

हेगड़े के खिलाफ अभियान में भी मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार ही है. इंका ने लोकायुक्त के पास राज्य सरकार के खिलाफ एक दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज कराए हैं. इसके अलावा उसने जनता सरकार के विरोधियों को एक या दूसरे बहाने से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए उकसाया है. राज्य भर की दीवारों पर बड़े-बड़े पोस्टर चिपकाए गए हैं जिनमें राज्य सरकार पर आर्थिक बदइंतजामी के आरोप दर्ज हैं. हेगड़े कहते हैं, "इंका तो पिछले साल से लोगों को गुमराह करने के अभियान में जुटी है पर अब तक उसे कुछ हासिल नहीं हुआ है."

केरल में भी इंका के तेवर जोशीले ही रहे. पिछले साल मार्च में वाममोर्चा सरकार के सत्तारूढ़ होने के कुछ ही महीनों बाद पार्टी सक्रिय हो गई. उसने आबकारी नियमों में संशोधन पर काफी हो-हल्ला मचाया और सरकार पर शराब की दुकानों को नियमित करके दिशानिर्देशों के उल्लंघन का आरोप लगाया. उसने यह आरोप लगाकर बवाल खड़ा कर दिया कि मार्क्सवादियों ने त्रिवेंद्रम में पार्टी मुख्यालय बनाने के लिए विश्वविद्यालय की जमीन हथिया ली है.

राज्यपालों की कार्रवाइयों से भी नई दिल्ली की मंशा झलकती है. आंध्र प्रदेश में कुमुदबेन जोशी और केरल में रामदुलारी सिन्हा को निर्देश है कि वे जिलों के दौरे पर जाकर केंद्र की उपलब्धियों का गुण-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गान करें. इस बीच तमिलनाडु के राज्यपाल पी.सी. अलेक्जेंडर अपने इंका समर्थक सलाहकार डॉ. एस.एस. सिद्धू के सहयोग से स्थानीय इंका नेताओं के साथ सक्रिय संबंध साधे हुए हैं. और उधर केंद्रीय खुफिया एजेंसियां भी दक्षिण के शासकों के खिलाफ असंतोष बोने में लगा दी गई हैं.

पर दक्षिण में अचानक इतनी दिलचस्पी क्यों? संसदीय आम चुनाव ज्यादा दूर न होने के मद्देनजर इंका जानती है कि उत्तर भारत में इस बार 1984 की वह लहर फिर नहीं चल पाएगी जिसके रहते उसे वहां 90 फीसदी सीटें मिली थीं. इस नुकसान की भरपाई के लिए वह दक्षिण में अपनी स्थिति पुख्ता करना चाहती है जहां पिछली बार उसे 129 में से 76 सीटें ही मिली थीं.

लेकिन इस रणनीति की सफलता प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता के साथ ही अधर में लटकी है. अपने सलाहकारों समेत वे हमले का निशाना बने हुए हैं. जिस तरह वे हेगड़े सरीखे दक्षिण के नेताओं से उलझे हैं उससे यह भी हो सकता है कि जिस कीचड़ को वे उछाल रहे हैं कहीं खुद भी उसी में ही न सन कर रह जाएं.

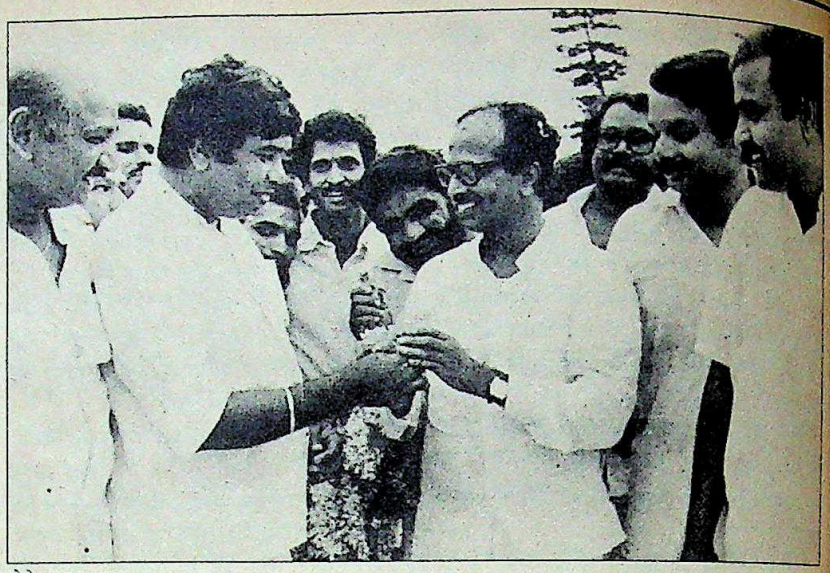

फोटो: मुश्ताक अहमद

पुजारी (चश्मा पहने) के साथ फर्नांडीस; और (बाएं) हेगड़े: घेराबंदी

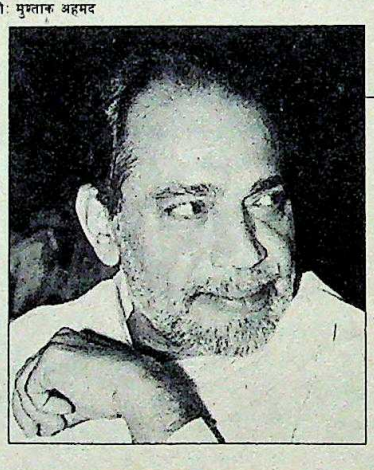

पुजारी की अगुआई में इंका ने हेगड़े सरकार के खिलाफ आरोप लगाने की मुहिम निरंतर जारी रखी है. इस जेहाद में उन्हें सफलता भी मिलती दिखती है

कर्नाटक

तलवार भांज रहे पुजारी

कर्नाटक में इंका की सोचने की शैली को मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े ने क्या खूब अंदाज में बयान किया है. राज्य सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के एक के बाद दूसरे आरोप का जिक्र करते हुए हेगड़े ने कहा, "उनका सिद्धांत है कि आरोप लगाते जाइए, कहीं-न-कहीं तो बात बनेगी और लोग सोचने लगेंगे कि दाल में कुछ काला है."

हमले लगातार जारी रहे हैं. दो साल पुराने अरक कांड को, जिसमें हेगड़े भी फंसे हैं, खूब उछाला गया है. विधानसभा में विपक्ष की नेता के.एस. नागरत्नम्मां ने कहा, "बिना प्रयोजन के विधान सौध में कुछ नहीं हो सकता." विधान परिषद में विपक्ष के नेता टी.एन नरसिंहमूर्ति ने हेगड़े को 'भ्रष्टाचार का अवतार' तक कह डाला. और विधान परिषद के ही मुख्य सचेतक के.एन. नागेगौडा ने तो मुख्यमंत्री पर पनडुब्बी सौदे में शामिल होने का आरोप भी लगा दिया.

यह रणनीति कारगर साबित होती लगती है. न सिर्फ सार्वजनिक निर्माणमंत्री एच.डी. देवगौडा का मामला लोकायुक्त के सुपुर्द किया गया है बल्कि हेगड़े ने खुद माना है कि वे भ्रष्टाचार मिटाने में नाकाम रहे हैं. इसी साल 2 मार्च को भाजपा नेता बी.बी. शिवप्पा ने देवगौडा, बी.ए. जिवीजिया और बी. सोमशेखर सरीखे मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए (देखें इंडिया टुडे, 31 मार्च) तो इंका के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई. इंका ने यह आक्रामक मुद्रा ऑस्कर फर्नांडीस के प्रदेश पार्टी अध्यक्ष रहते समय अख्तियार की थी.

इसके बाद पिछले साल सितंबर में जनार्दन पुजारी अध्यक्ष बने. उन्होंने जनता सरकार के खिलाफ वित्तीय घोटालों के आरोपों को लेकर जेहाद छेड़ दिया. आज कर्नाटक के बहुत से लोग यदि सरकार को भ्रष्ट कहते हैं तो इसका श्रेय पुजारी को ही जाता है.

जनता पार्टी के नेताओं को भी पता है कि उसके विरोधियों की मंशा क्या है. कर्नाटक जनता पार्टी अध्यक्ष एम.पी. प्रकाश कहते हैं, "बोफोर्स सौदे की वजह से राजीव सरकार की छवि भ्रष्टाचार से जुड़ गई है. अब पार्टी यह दाग धो नहीं पा रही इसलिए वह सभी गैर-इंका मुख्यमंत्रियों की ईमानदारी पर प्रश्नचिन्ह लगा रही है."

पुजारी को दूसरे क्षेत्रों में भी सफलता मिल रही है. उनका मानना है कि "प्रदेश कार्यालय में बैठकर पार्टी नहीं बनाई जा सकती." इसलिए वे व्यापक पैमाने पर जनसंपर्क अभियान छेड़े हुए हैं. पदभार ग्रहण करने के छह महीनों के भीतर ही उन्होंने 1,522 कस्बों और गांवों की यात्रा कर ली. उन्हें नई दिल्ली में मंत्री की जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं, फिर भी महीने में 20 दिन वे कर्नाटक के दौरे पर रहते हैं.

15 महीने पहले फर्नांडीस के कार्यकाल में ही जनता पार्टी के मुकाबले इंका की बढ़ती लोकप्रियता साफ दिखने लगी थी. हालांकि पंचायत चुनावों में अधिकतर सीटों पर जनता पार्टी ने कब्जा किया था पर उसे इंका के 44.25 फीसदी के मुकाबले 45.43 फीसदी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

...ल ही हासिल हुए थे. राज्य के एक और ...महत्वपूर्ण इंकाई और हाल ही में बने केंद्रीय ...योजना राज्यमंत्री जाफर शरीफ कहते हैं, ...जनता पार्टी को तो तकनीकी कामयाबी ही ...मिली, नैतिक जीत तो हमारी हुई थी. अगले ...विधानसभा चुनावों में कर्नाटक की बागडोर ...हमारे ही हाथ होगी.''

पार्टी निश्चित रूप से इस लक्ष्य को ...हासिल करने की कोशिश में दिखती है. इस ...मकसद की पूर्ति के लिए वह:

- हेगड़े को पशोपेश में पड़े एक ऐसे ...मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर रही है जो अपनी ...क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं के कारण राज्य की ...उपेक्षा कर रहा है.
- जनता पार्टी में अंदरूनी लड़ाई को ...भड़काने की कोशिश कर रही है.
- केंद्रीय सरकार की गरीब ग्रामीणों के ...लिए चलाई जा रही योजनाओं में लगे बीच ...के लोगों को हटाकर उनमें पार्टी कार्यकर्ताओं ...को भर रही है.
- जनता शासन में धन की कमी से धीमे ...पड़े ग्रामीण विकास पर जोर दे रही है.
- केंद्रीय बजट के किसान समर्थक होने का ...प्रचार कर रही है.
- ग्रामीण इलाकों में कमजोर तबकों और ...दलितों में बढ़ती असुरक्षा की भावना को ...भड़काकर जनता पार्टी को ऊंची जातियों की ...पार्टी के तौर पर पेश कर रही है.

दलितों और अल्पसंख्यकों का विश्वास ...हासिल करने में पुजारी के बहुचर्चित कर्ज ...मेलों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है. जनता ...पार्टी की इस जायज आलोचना को भी, कि ...अगले वोट पक्के करने के लिए सोचे-समझे ...ढंग से बैंक कर्जे बांट रहे हैं, केंद्रीय मंत्री ने ...अपने पक्ष में भुनाया. हेगड़े भी मानते हैं कि ...जनता ने खुलकर बैंकों का दुरुपयोग किया ...और गरीबों के दोस्त के बतौर उभरने में वे ...काफी कामयाब रहे हैं.''

कर्ज मेलों की लोकप्रियता ने अब राज्य ...सरकार को इसी तरीके की दूसरी योजनाएं ...चलाने पर मजबूर किया है. ऐसी एक योजना ...अल्पसंख्यकों, पिछड़े तबकों और दलितों के ...लिए कर्ज शिविर लगाने की है जिसे राज्य के ...कुछ निगमों ने धन मुहैया कराया है. इस ...तहत ऐसे दो शिविर शिमोगा और हुबली ...जिलों में लगाए गए.

लेकिन इंका को उसकी चाल से ही मात ...देने की जनता पार्टी की कोशिशों से राज्य ...इकाई में आशा बढ़ी ही है. इंका महासचिव ...जनार्दन पुजारी विश्वासपूर्वक कहते भी हैं, ''लोग ...फिर से इंका की वापसी चाहते हैं और जनता ...दल अपनी कब्र खोद रही है.''

उनकी इस बात में दम भी है. पिछले साल जनता पार्टी के आंतरिक मतभेद बढ़े. हेगड़े के दल के लोग ही सरकार की आलोचना करें, इससे अब किसी को हैरानगी नहीं होती. युवा इंका ने तो जनता पार्टी के नेताओं की इन टिप्पणियों के पोस्टर भी छपवा दिए जिनमें पूछा गया था: हेगड़े जी, क्या आप इन बातों का जवाब देंगे?

जनता पार्टी की गुटबंदी ने निश्चय ही इंका का काम आसान कर दिया है. लेकिन पुजारी भी कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहते, वह भी ऐसे राज्य में जो पांच साल से इंका के दायरे से बाहर है.

आंध्र प्रदेश

मुहिम मुख्यमंत्री के खिलाफ

आंध्र प्रदेश में इंका एक ही बात पर लगातार जमी रही है. उसने मुख्यमंत्री नंदमूरि तारक रामराव पर भ्रष्टाचार के ढेरों आरोप लगाए हैं. पिछले पखवाड़े उसने साबित भी कर दिखाया कि वह आरोपों के अखाड़े के खिलाड़ियों को कितना महत्व देती है. इंका ने द्रोणमराजू सत्यनारायण को राज्यसभा के लिए नामजद किया. आंध्र प्रदेश से पार्टी को यही एक सीट मिली भी. सत्यनारायण का योगदान सिर्फ इतना है कि उन्होंने हाईकोर्ट में रामराव के खिलाफ याचिकाएं दायर कीं. मुख्यमंत्री पर लगे भ्रष्टाचार और कुनबा-परस्ती के आरोपों की न्यायिक जांच की मांग की और अदालत से याचना की कि वह मुख्यमंत्री को पद से हटने का आदेश दे (देखें इंडिया टुडे, 30 नवंबर '87). दो याचिकाएं अभी भी अदालत में विचाराधीन हैं.

रामराव के खिलाफ कोई ठोस मुद्दा न मिलने पर जे. वेंगलराव की अगुआई में इंका ने उन्हें व्यक्तिगत आरोपों का निशाना बनाना शुरू किया. पिछले महीने रंगारेड्डी जिले में हुए स्थानीय चुनावों के दौरान वेंगलराव ने मुख्यमंत्री को 'झूठा' और 'केसरियाधारी लंपट' तक कह डाला.

मुख्यमंत्री को नीचा दिखाने के लिए पूरी केंद्रीय मशीनरी भी मैदान में उतार दी गई. आयकर विभाग उनकी पारिवारिक संपत्ति का कई बार आकलन कर चुका है. अब मुख्यमंत्री के परिवार के लोग संपत्ति का कम मूल्य बताने के मामले में फंसा लिए गए हैं.

शुरुआती हमलों से तेलुगु देशम के प्रमुख

अदालती मुकदमों से रामराव की छवि हालांकि बहुत हद तक धुंधलाई ही पर वेंगलराव इन सबका कोई फायदा उठाने में सफल नहीं रहे हैं

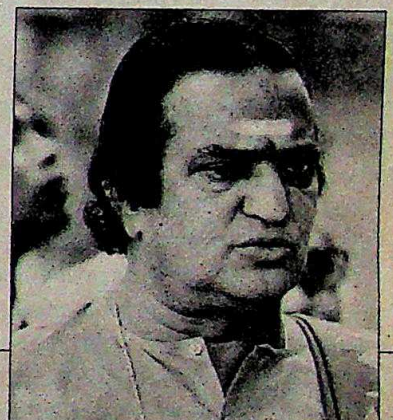

(दाएं) रामराव; और आमसभा में वेंगलराव: व्यक्तिगत आरोप

जनता स्टुडियो

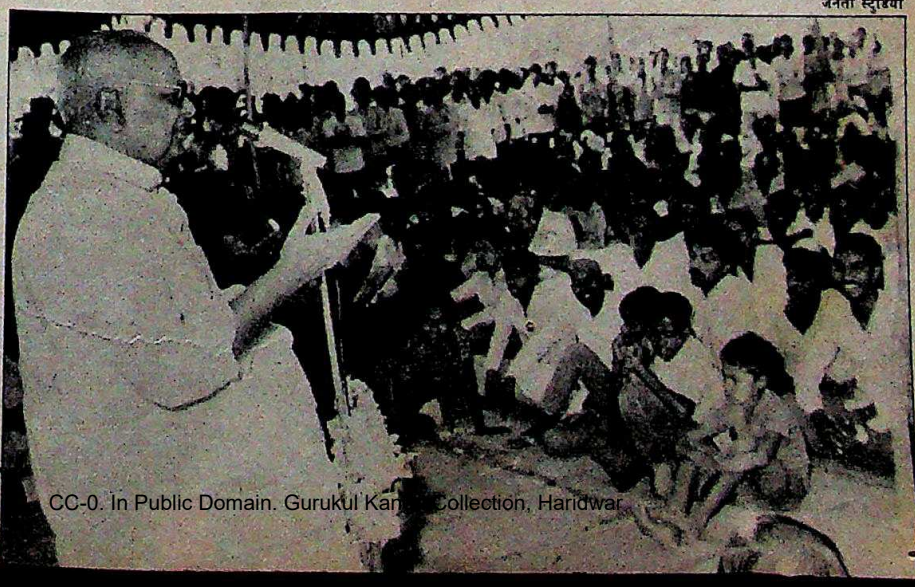

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भी घबरा गए थे पर अब वे जवाबी हमला करने लगे हैं. सभाओं में वे लोगों को समझाते हैं कि उन्होंने तो फिल्म स्टार रहते वक्त पैसा कमाया था लेकिन इंका के अनेक पूर्व मंत्रियों ने धन-दौलत कहां से जमा की. इंका को 'बेहद पतित संस्था' की संज्ञा देने और उसके सदस्यों को 'घूसखोर' बताने में वे कोई कसर बाकी नहीं रखते.

लेकिन इस सबसे इंका के तेवर ठंडे नहीं पड़े हैं. सत्यनारायण की याचिका के बाद से तो राजीव गांधी महीने में औसतन एक बार आंध्र प्रदेश के दौरे पर आकर तेलुगु देशम अध्यक्ष पर आरोपों की बौछार जरूर करते हैं. पिछले साल दिसंबर में गृहमंत्री बूटा सिंह ने तो हद ही कर दी. उन्होंने रामराव पर 'अलगाववादी और राष्ट्रविरोधी ताकतों' की मदद करने का आरोप लगाया था.

राज्य पर पकड़ मजबूत करने की अपनी योजना के तहत इंका ने नाफेड, स्टेट फार्म्स कार्पोरेशन और तंबाकू सलाहकार परिषद सरीखे केंद्रीय संगठनों में आंध्र प्रदेश के अपने दर्जन भर पूर्व सांसदों और विधायकों की भर्ती की है. इससे न सिर्फ उनका अपना प्रभाव बढ़ेगा बल्कि इन संगठनों की सुविधाओं के बूते पर वे राज्य भर का दौरा भी कर सकेंगे.

लेकिन इंका के सक्रिय कार्यकर्ता इस मुहिम के स्वरूप से संतुष्ट नहीं हैं. वेंगलराव की कार्यप्रणाली से तो वे खासकर परेशान हैं. उन्हें लगता है कि केंद्रीय मंत्री और राज्य इंका अध्यक्ष के रूप में वे अपनी दोहरी जिम्मेदारी ठीक तरह से नहीं निभा रहे. पूर्व मंत्री पी. गोवर्धन रेड्डी कहते हैं, "वेंगलराव पार्टी के काम के लिए तो शनिवार और रविवार को ही यहां आते हैं."

रेड्डी का उनके बारे में ख्याल गलत नहीं. वेंगलराव पार्टी की राज्य कार्यकारिणी को ही सक्रिय कर पाए हैं. पार्टी के एक नेता बताते हैं कि जिला और मंडल इकाइयां निष्क्रिय पड़ी हैं और ग्रामीण स्तर पर कार्यकर्ताओं को भर्ती करने का तो कोई कार्यक्रम तय ही नहीं हुआ है.

एक दूसरे पहलू से भी स्थानीय पार्टी नेता परेशान हैं और वह यह कि राज्यपाल कुमुदबेन जोशी पार्टी की ओर से आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं. ज्यादातर का मानना है कि पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करके दरअसल वे इंका की छवि को ही नुकसान पहुंचा रही हैं.

रामराव और राज्यपाल के संबंध पहले से ही बिगड़े पड़े हैं और हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल ने भी उनसे अपने खर्चों में कटौती करने को कहा है. तिस पर भी राजीव ने फरवरी में आंध्र प्रदेश के अपने दौरे में राज्यपाल को प्रकाशम जिले के कपास उत्पादकों की आत्महत्या की घटनाओं की रिपोर्ट देने को कहा हालांकि मुख्यमंत्री इस संबंध में विस्तृत ज्ञापन उन्हें पहले ही दे चुके थे.

मुख्यमंत्री इन कामों में जरा भी कोताही नहीं बरतते क्योंकि उन्हें अंदेशा बना हुआ है कि इंका कर अधिकारियों की मदद से उन्हें फिर परेशान कर सकती है. हालांकि यह पक्के तौर नहीं कहा जा सकता कि रामराव की लोकप्रियता खत्म हो रही है पर वेंगलराव भी मुख्यमंत्री को हटाने के अपने दावे को तब तक अमली जामा नहीं पहना सकते जब तक कि वे अपनी राज्य इकाई को चुस्त-दुरुस्त नहीं कर लेते.

—अमरनाथ के. मेनन

केरल

बंधी मुट्ठी लाख की

यह लड़ाई का दौर शुरू होने का ही संकेत था. पिछले महीने केरल की राज्यपाल रामदुलारी सिन्हा ने मुख्यमंत्री ई.के. नयनार को तलब करके आदेश दिया कि वे 15 मार्च को विपक्षी दलों के भारत बंद के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने का माकूल बंदोबस्त करें.

राज्य प्रशासन में सिन्हा के हस्तक्षेप से अगले ही दिन विधानसभा में हंगामा खड़ा हो गया. आरोप लगाया गया कि सिन्हा शायद केंद्र के इशारे पर काम कर रही हैं. इसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष वर्कला राधाकृष्णन पर धावा बोला गया. मामला दो इंका विधायकों की सदन से मुअत्तली तक पहुंचा. बाद में इंका ने राधाकृष्णन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया. मार्क्सवादियों की अगुआई वाले वाममोर्चे से राज्यपाल की तनातनी राज्य सरकार के तख्ता पलट की इंकाई कोशिशों की ताजा कड़ी है.

इंका को इस खेल में अभी तक जो कामयाबी मिली है, उसकी वजह उसमें हाल ही में कायम हुई एकता है. राज्य पार्टी अध्यक्ष ए.के. एंथनी और पूर्व मुख्यमंत्री के. करुणाकरन जिस तालमेल से काम कर रहे हैं उससे खुद राजीव गांधी भी हैरत में हैं.

यह पार्टी के भीतर तालमेल का ही सबूत है कि वह हर बात का फायदा उठाने लगी है. त्रिवेंद्रम में मार्क्सवादियों के राज्य कार्यालय की जमीन का मुद्दा जिस तरह से उछाला गया उससे यही जाहिर होता है. हालांकि दो महीने पहले जब इंका ने आरोप लगाया था कि माकपा न सिर्फ इस जमीन पर गैरकानूनी

मार्क्सवादियों की रक्षात्मक मुद्रा की वजह यह है कि इंका एंथनी की अगुआई में एकजुट हो गई है. पार्टीजनों में तालमेल देखकर खुद राजीव भी हैरत में हैं

(दाएं) नयनार; और राज्य सचिवालय पर भाषण देते एंथनी: जेहादी तेवर

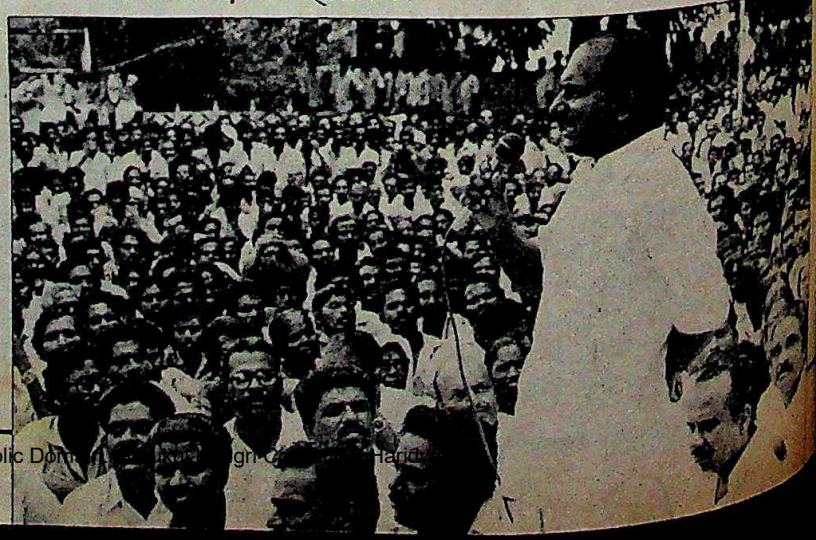

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. Harid

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

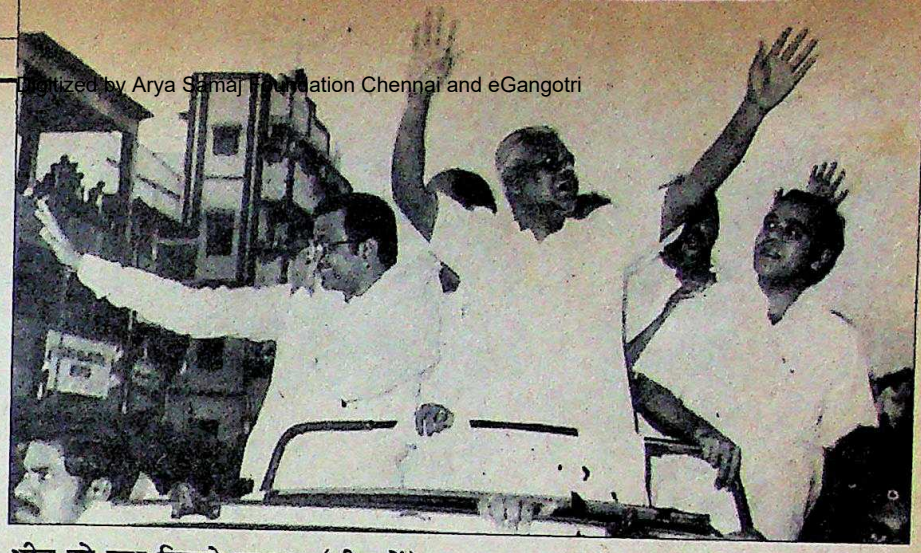

भीड़ को हाथ हिलाते मूपनार (बीच में); और करुणानिधिः बढ़ती उम्मीदें

मूपनार की अगुआई में इंका में वर्षों बाद यह उम्मीद जगी है कि वह तमिलनाडु में अकेले सत्ता पर काबिज हो सकती है और पार्टीजनों की महत्वाकांक्षाएं भी बेहद बढ़ गई हैं

तमिलनाडु

सत्ता में लौटने की आस

अगर किसी राज्य में इंका पूरी गंभीरता से सत्ता में लौटने की आस लगाए बैठी है तो वह है तमिलनाडु. यहां पिछले दो दशकों से बड़ गद्दी से बाहर रही है. पार्टी की पतवार के. मूपनार के हाथ में आ जाने से इंका की उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं.

पिछले पखवाड़े तिरुचि में मूपनार की रामसभा जिस तरह कामयाब रही उससे इंके पार्टीजनों की महत्वाकांक्षाएं बेहद बढ़ गई हैं. मद्रास दूरदर्शन ने भी इसे बढ़-चढ़कर दिखाया. मूपनार अब भावी मुख्यमंत्री के रूप में पेश किए जा रहे हैं.

पार्टी न सिर्फ सत्ता में लौटने की आस लगाए बैठी है बल्कि वह इसे अन्नाद्रमुक के जयललिता गुट का पल्लू थामे बिना अपने ही बूते पर कर भी लेना चाहती है. तमिलनाडु इंका के एक पदाधिकारी कहते हैं, "हमारे पार्टी नेताओं को विश्वास है कि हम अकेले ही लड़कर जोरदार जीत हासिल कर सकते हैं."

पार्टी सोची-समझी नीति के तहत राज्यपाल पी.सी. अलेक्जेंडर के जरिये यह जताने की कोशिश कर रही है कि केंद्र स्वच्छ और कुशल प्रशासन दे सकता है. राज्यपाल का पद संभालते ही अलेक्जेंडर ने संकेत दिया, "मैं नागरिक योजना की खामियों को खोज रहा हूं और इसके मूल्यांकन के बाद कामकाज सुधारूंगा." उन्होंने पीने के पानी, सड़कों पर बत्तियां और स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के कुछ बड़े-बड़े वायदे भी किए थे. उन्होंने कहा था, "मैं नागरिक सेवाओं को बेहतर कामकाज के लिए तैयार कर रहा हूं. मैं लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह अफसरशाही का शासन नहीं है."

राष्ट्रपति शासन के तहत राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों-जनजातियों के छात्रों के वजीफे और विशेष भत्ते बढ़ाकर दुगने कर दिए हैं. राज्यपाल हर परिवार को हर महीने राशन में 12 किलो चावल मुहैया कराने का बंदोबस्त भी कर रहे हैं. केंद्र ने भी तमिलनाडु के चावल का मासिक कोटा 50,000 से बढ़ाकर 80,000 टन कर दिया है.

राज्यपाल इंका के हितों के प्रति कितने सचेत हैं, यह बात आसानी से दिख जाती है. प्रदेश पार्टी अध्यक्ष बनने के तुरंत बाद मद्रास पहुंचते ही मूपनार ने अलेक्जेंडर को एक लंबा-चौड़ा ज्ञापन दिया. इसमें उन्होंने लगान और बिजली के बिलों का बकाया न जमा करने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई न करने का अनुरोध किया था. राज्यपाल ने इसे तुरंत मान भी लिया.

पर द्रमुक अध्यक्ष एम. करुणानिधि इंका और राज्यपाल के इस गठजोड़ की आलोचना कर रहे हैं. उदाहरण के लिए उन्होंने बताया कि तमिलनाडु एक अर्से से केंद्र सरकार से कावेरी जल विवाद पर एक पंचाट बैठाने की मांग कर रहा था. पर "अब नई दिल्ली के एजेंट अलेक्जेंडर ने ज्यों ही पंचाट का अनुरोध किया, केंद्र ने इसे मान लिया. यह सब चुनाव के लिए इंका की कवायद है."

मूपनार के अलावा केंद्रीय गृह राज्यमंत्री पी. चिदंबरम भी पार्टी काम के लिए हफ्ते के आखिरी दिन तमिलनाडु में ही गुजारते हैं. वे उत्साह से कहते हैं, "आखिर हम तमिलनाडु की सत्ता हासिल कर ही लेंगे." वर्षों बाद मौका आया है कि ज्यादातर इंकाई इसे बेवजह की उम्मीद नहीं मान रहे हैं.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ए.बी. देवय्या

शौर्य की बिसरी गाथा

वीरगति प्राप्त उड़ाके का 23 साल बाद सम्मान

राष्ट्रपति रामस्वामी वेंकटरामन अगले पखवाड़े स्क्वाड्रन लीडर अज्जमदा बोपय्या देवय्या को महावीर चक्र से सम्मानित करेंगे. करीब 23 साल पहले पाकिस्तान के सबसे दुर्जेय— सरगोधा— हवाई अड्डे पर दुस्साहसिक हवाई हमला करते हुए वे वीरगति को प्राप्त हुए थे. तब वे एक पुराना 'मिस्टीर' (लड़ाकू विमान) उड़ा रहे थे. 7 सितंबर 1965 को उनकी गुमशुदगी का एलान किया गया. 22 दिन चली उस लड़ाई पर शोध करने वाले विशेषज्ञों को अब जाकर एक अविश्वसनीय-सा तथ्य हाथ लगा है; कि जमीन पर गिरने से पहले देवय्या ने अपने 'मिस्टीर' से दुगुने तेज, ताकतवर और 'साइडविंडर' प्रक्षेपास्त्रों से लैस उस समय के अत्याधुनिक पाकिस्तानी 'स्टारफाइटर' एफ-104 को मार गिराया था. तथ्य बताते हैं कि यह अदम्य साहस, बलिदान और उड़ान की कारीगरी की एक बेमिसाल कहानी है. यह खास रिपोर्ट लिखने के लिए विशेष संवाददाता ***शेखर गुप्ता*** *ने शोधकर्ताओं और युद्ध के दूसरे भागीदारों से तथा प्रमुख संवाददाता* ***अनीता प्रताप*** *ने बंगलूर में बोपय्या के गौरवान्वित परिवार से मुलाकात की:*

कार्रवाई बहुत ही संक्षिप्त, तेज और उत्तेजक थी. भारतीय वायुसेना (आईएएफ) के 'मिस्टीर' लड़ाकू विमानों ने नीचे उड़ान भरते हुए जैसे ही सरगोधा हवाई अड्डा पार किया, पाकिस्तानी वायुसेना (पीएएफ) का गश्त पर निकला 'स्टार-फाइटर' टोही विमान उनके पीछे लग गया. चूंकि भारतीय विमानों का ईंधन खत्म हो चला था और उनमें टिके रहने की वैसी क्षमता भी नहीं थी इसलिए 'स्टारफाइटर' शिकार मिलने की उम्मीद कर रहा था.

एक 'मिस्टीर' ज़द में आते ही पाकिस्तानी लड़ाकू विमान ने उस लड़ाई का सबसे मारक अस्त्र-साइडविंडर प्रक्षेपास्त्र-उस पर दाग दिया लेकिन 'मिस्टीर' ने फुर्ती से बचाव करके उसे चौंका दिया और प्रक्षेपास्त्र ज़मीन पर जा गिरा. इस पर पाकिस्तानी जहाज ने 'मिस्टीर' के एकदम करीब आकर अपनी छह नलियों वाली 'वल्कान' तोप से उस पर धुंआधार गोलाबारी की और दूसरे शिकार मार गिराने के लिए ऊपर उठ गया. पाकिस्तानी उड़ाके को पक्का यकीन था कि उसके तेज-तर्रार 'स्टारफाइटर' के सामने पुराने 'मिस्टीर' के टिकने की दूर-दूर तक कोई संभावना नहीं है.

इसलिए पाकिस्तानी उड़ाके को यह भान भी नहीं हुआ कि अभी-अभी जिस पर उसने घातक मार की वह शेरदिल भारतीय न तो नीचे जा गिरा और न ही मैदान से बाहर हुआ बल्कि अपने चोट खाए जहाज को संभालते हुए वह अभी भी उसका पीछा कर रहा था. देवय्या की 30 मिमी तोपों की मार इतनी सटीक थी कि पाकिस्तानी जहाज का बचना मुश्किल था. 'स्टारफाइटर' के कॉकपिट में धुआं भर गया और फ्लाइट लेंफ्टिनेंट अमजद हुसैन जहाज पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे थे. लेकिन आखिर-कार वे जहाज से छतरी के सहारे कूदने में कामयाब हो गए. उधर देवय्या जान बचाने के लिए जहाज से बाहर कूदने की पुरानी सीट के खुलने का बहुत देर तक इंतजार करते रहे. आखिरकार उनका जहाज पाकिस्तानी जमीन पर धराशायी हो गया. और उनके खेत रहने के साथ ही उनके अप्रितम शौर्य की गाथा भी वहीं दबकर रह गई.

1965 की लड़ाई शुरू होते ही पाकिस्तानी वायुसेना तेजी से हमले पर उतर आई थी. उसने आकाश में और जमीन पर कई शुरुआती कामयाबियां हासिल कर ली थीं. इस कारण आईएएफ ने सरगोधा पर जवाबी हमला करने का फैसला किया. इसका जिम्मा दिया गया— जालंधर के नजदीक आदमपुर स्थित फर्स्ट स्क्वाड्रन 'टाइगर्स' को. इसके कमांडिंग अफसर, तब के विंग कमांडर ओ.पी. तनेजा चार लड़ाकू विमानों के पहले जत्थे का नेतृत्व कर रहे थे. इसके पीछे करीब 100-100 गज दूरी बनाए बाकी दो जत्थे चल रहे थे. लेकिन गोपनीयता बनाए रखने के लिए पायलटों को रेडियो संपर्क करने की मनाही कर दी गई थी. नतीजतन घुप अंधकार के कारण जत्थे का एक जहाज भटक गया. दो दूसरे जहाजों के इंजनों में कुछ गड़बड़ी हो गई और वे लौट आए. इस तरह अतिरिक्त पायलट देवय्या से उस अभियान में उड़ान भरने को कहा गया.

लेकिन उनके स्क्वाड्रन में कोई जहाज बाकी न बचने के कारण उन्होंने साथ के 32 स्क्वाड्रन से एक जहाज उधार लिया. इसलिए वे अभियान पर निकले बाकी जहाजों से काफी पीछे थे. अब अवकाशप्राप्त ग्रुप कैप्टन तनेजा याद करते हैं, "अगर योजना के मुता-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सब कुछ ठीक-ठाक चला होता तो देवय्या को उड़ान भरनी ही नहीं लेकिन लगता है उनकी मौत ही उन्हें ले गई." फिर परंपरा के मुताबिक साल देवय्या को मृत घोषित कर दिया गया. विडंबना यह रही कि उन्होंने क्या कुछ कर डाला था इसका सबूत सबसे पहले में पाकिस्तानी सूत्रों के मार्फत ही पीएफ ने अपना इतिहास लिखने के एक अंग्रेज लेखक जॉन फ्रीकर को सौंपा था. फ्रीकर ने वैसा ही लिखा कि उनसे उम्मीद थी : उन्होंने लिखा कि ने बड़ी आसानी से कामयाबी हासिल ली थी, जबकि भारतीय वायु सेना को एक कामयाबी का श्रेय दिया जा सकता यह कि उसके एक बहुत ही मामूली

पारिवारिक एलबम का चित्र; और (नीचे) सुंदरी: आज का अकेलापन

राष्ट्रपति भवन के मंच पर जाते ही उनके जीवन का अवसाद गौरव के नए प्रभामंडल में घुल जाएगा. सुंदरी कहती हैं, "मैं गौरवान्वित महसूस कर रही हूं"

के 'मिस्टीर' जहाज ने 7 सितंबर की में मरगोधा के ऊपर एक पाकिस्तानी फाइटर' को मार गिराया.

नेजा बताते हैं, "फ्रीकर की किताब ने ही मैंने बड़े अफसरों से संपर्क किया कहा कि यह काम देवय्या ने ही किया ." उस दिन सिर्फ दो ही पायलट गुम हुए — मदेरे देवय्या और शाम को फ्लाइट लेफ्टिनेंट बाबुल गुहा.

लेकिन पिछले साल तक इस मामले में की के कान पर जूं तक नहीं रेंगी. सरकार 1965 के युद्ध का आधिकारिक लेखन लिखने में व्यस्त सुरक्षा मंत्रालय के इतिहास विभाग के हाथों फ्रीकर की किताब पहुंची. संयोगवश शोधकर्ताओं में से एक एअर मार्शल प्रीतम सिंह थे. प्रीतम सिंह ने एक लड़ाकू 'नैट' पायलट के रूप में 1965 की लड़ाई लड़ी थी. अब वे जोधपुर में वायुसेना के अड्डे के स्टेशन कमांडर हैं. वे कहते हैं, "मैं 'मिस्टीर' के सभी पायलटों को जानता था. इसलिए मैंने उन्हें खोजना और उनसे पूछताछ करना शुरू किया."

उन्होंने पाकिस्तानी रेड़ियो से प्रसारित एक एफ-104 विमान के नष्ट होने की सूचना पर गौर किया, उस अभियान में शामिल सभी लोगों और तनेजा से विस्तृत बातचीत की और सभी सबूत इकट्ठा किए.

उन्हें याद आया कि देवय्या ने जिस पाकिस्तानी-अमजद हुसैन के जहाज को मार गिराया था, उसने 1971 के युद्ध में भी भाग लिया था और अमृतसर के पास उसके जहाज को फिर मार गिराया गया और उसे बंदी बना लिया गया था. उन्होंने हुसैन से हुई पूछताछ की रिपोर्ट ढूंढ़ निकाली लेकिन उसमें 1965 की लड़ाई का कोई जिक्र नहीं था.

लेकिन प्रीतम सिंह ने हार नहीं मानी. उन्होंने वायुसेना के आलाकमान के सामने अपने इकट्ठा किए सारे सबूत पेश किए. वे कहते हैं, "मेरी कोशिश थी कि आईएएफ यह बात मान ले कि ऐसी लड़ाई सचमुच हुई थी."

दस्तावेजों और देवय्या के प्रशस्ति पत्रों से पता चलता है कि सरगोधा पर हमले के दौरान जहाज का ईंधन चुक जाने की हालत आ जाने पर भी उन्होंने पीछे रहकर 'स्टार-फाइटर' से जूझने का निश्चय किया.

हालांकि भारतीय वायुसेना अब जाकर कहीं अर्से से खोए अपने हीरो को सम्मानित कर रही है पर इस बात में कोई शक नहीं कि देवय्या के बलिदान से आज सबसे ज्यादा गौरवान्वित अगर कोई महसूस कर रहा है तो वह है— उनकी पत्नी सुंदरी देवय्या. 23 साल पहले 30 अगस्त की शाम को उनके बहादुर पति सिकंदराबाद से पंजाब में रणक्षेत्र के लिए रवाना हुए थे. अब 51 साल की हो चुकी इस महिला ने तब से अपनी दो बेटियों को पाल पोसकर बड़ा किया. श्रीमती देवय्या का नीरस वैधव्य जीवन पूरी तरह अपनी प्यारी बेटियों— 24 वर्षीय स्मिता और 23 वर्षीय प्रीता के इर्द-गिर्द ही सिमटा रहा है. इस सम्मान से उस अतीत की याद ताजा हो आई जो दुखदायी तो है पर महिमामंडित भी. वे कहती हैं, "मैं स्वयं को अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रही हूं.

पर अतीत को याद करते ही उनका स्वर हल्के विषाद से भीग उठता है. उन्हें 30 अगस्त की वह शाम याद है जब भारतीय वायुसेना का एक पत्र-वाहक उनके पति के लिए सिकंदराबाद के उनके घर में तार लाया था. उन्हें 15 दूसरे पायलटों के साथ तुरंत आदमपुर पहुंचना था. "मुझे स्थिति की गंभीरता का एहसास नहीं था पर तार से मेरे पति बुरी तरह परेशान हो उठे थे वे लगातार सिगरेट पिए जा रहे थे. पर उस वक्त आठ मास की रही प्रीता विरोध करती है, "लेकिन मां, वे परेशान नहीं थे. वे बड़े बहादुर जो थे."

पति की मृत्यु के बाद श्रीमती देवय्या कूर्ग में अपने भाई जोयप्पा के साथ करीब पांच साल रहीं. बाद में वे बंगलूर चली आईं. वे बताती हैं, "मैं वैवाहिक जीवन के सिर्फ तीन साल ही बिता पाई थी. हां, कई ऐसे मौके भी आए जब मेरे और बच्चों के लिए जिंदगी निहायत बोझ मालूम पड़ी."

लेकिन अगले पखवाड़े जब वे राष्ट्रपति भवन में बने मंच पर कदम रखेंगी और उनके बहादुर पति को सच्चे राष्ट्रीय हीरो का सम्मान दिया जाएगा तब उनके जीवन के बेहतर वर्षों को लीलने वाली यह तिक्तता, अवसाद और निराशा गौरव के नए प्रभाव-मंडल में घुलकर शायद बेअसर हो जाए.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जोधपुर के बंदी

सियासी खेल के शिकार

जो आजाद हुए उन्हें जिंदगी दुश्वार लगती है

ऑपरेशन ब्लूस्टार के बाद से अब तक बिना किसी सुनवाई के जोधपुर जेल में नजरबंद 365 सिखों के मामले पंजाब और उसके बाहर के विभिन्न राजनैतिक विचार-धाराओं के लोगों ने बार-बार उठाए हैं. केंद्र ने इन बंदियों को राजनैतिक मोहरों के रूप में इस्तेमाल किया. पहली बार राजीव-लोंगोवाल समझौते के तहत उनकी रिहाई का वायदा किया गया; फिर मुख्यमंत्री बरनाला को इराडी पंचाट का फैसला मनवाने के लिए भी इस मुद्दे का उपयोग किया गया. अब जबकि सरकार ने पंजाब मसले पर एक नई परंतु अस्पष्ट सी पहल की है तो इनमें से 40 नजरबंद लोगों को बेकसूर मानकर छोड़ दिया है. जोधपुर में इतने लंबे अरसे तक सीखचों के पीछे रहे ये लोग कौन हैं, किन हालात में उन्हें गिरफ्तार किया गया और इस बुरे वक्त का सामना वे और उनके घर वाले किस तरह करते रहे, इस बारे में वरिष्ठ संवाददाता ***विपुल मुद्गल*** *की रिपोर्ट:-*

पैंतीस बरस के दीवान सिंह ने कहा, "मुझे लगता था कि हमारी चौथी होली भी सीखचों के पीछे ही बीत जाएगी." लेकिन एकाएक उन्हें जोधपुर जेल के दूसरे 39 नजर-बंद लोगों के साथ बैरकों से बाहर निकाल एक जीर्ण-शीर्ण हाल में ले जाया गया.

वहां मौजूद भव्य व्यक्तित्व वाले अधेड़ सरकारी अधिकारी ने उन लोगों से कहा, "आप लोगों को रिहा किया जा रहा है. आप लोगों के खिलाफ अब कोई मामले नहीं हैं. आप सभी बेकसूर हैं." दीवान सिंह बुदबुदाए, "मैं जानता था कि सरकार को एक न एक दिन अपनी गलती का एहसास जरूर होगा."

लेकिन जो लोग अब भी जेल में बंद हैं उनके बारे में सरकार को शायद और देर में एहसास हो. राज्यपाल सिद्धार्थशंकर राय के वायदे के मुताबिक यदि उन्हें जल्दी रिहा भी कर दिया गया तब भी वे पहले जैसी सामान्य जिंदगी शायद ही जी पाएं. हाल ही में आजादी पाए लोगों के अनुसार जोधपुर जेल

इंदरजीत कौर ऑपरेशन ब्लूस्टार के दौरान हुई गोलीबारी में फंस गई थीं, उन्हें बिलावजह 45 महीने जेल में गुजारने पड़े

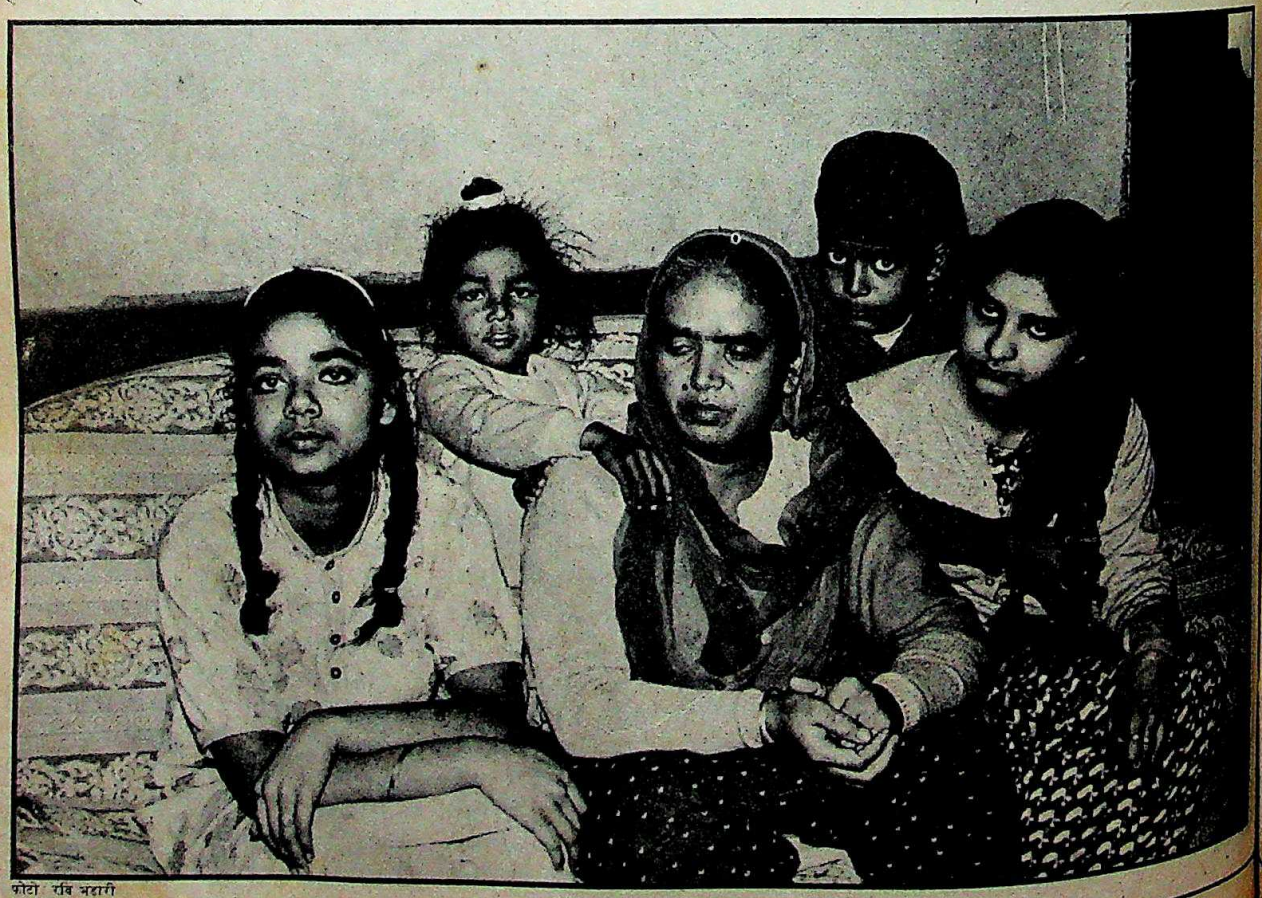

फोटो: रवि भंडारी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पीटीआई

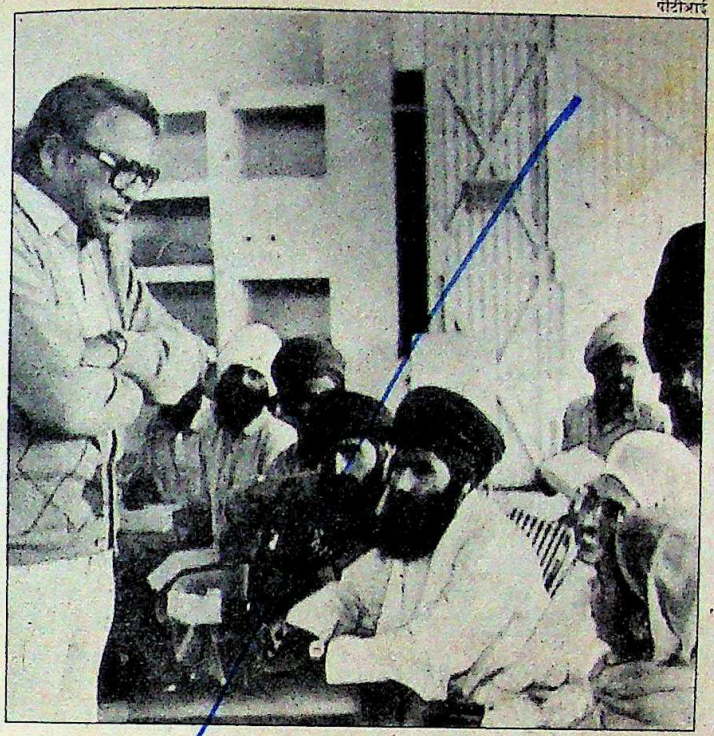

सुनहरे बालों वाले निहंग मक्खन सिंह को डर है कि जोधपुर जेल के बंदियों में से ज्यादातर का दिमागी संतुलन गड़बड़ा जाएगा

रिहा बंदियों के साथ रायः देर से हुआ इंसाफ

बंद कम-से-कम 50 लोग
न हो गए हैं. रनियां गांव
65 वर्षीय चंदन सिंह का
है, "मेरी ही बैरक में
लोग पागल हो गए. उनके
हैं: मेजर सिंह, सतनाम
जसवंत सिंह और एक
उत्तर प्रदेश का है. इन
को कई-कई दिनों तक या
हफ्तों तक तनहाई में
दिया जाता था."

कोटला डूम गांव के 70
निहंग मक्खन सिंह बताते
"अगर उन लोगों को लंबे
तक बंद रखा गया तो
में कई और लोगों की
हालत खराब हो
." यह बूढ़ा निहंग याद
है, "कड़ी सुरक्षा वाली
जेल के अफसरों के लिए
में कई बार पगली घंटी
बजवा देना आम बात हैं. उनका कहना है कि मौत के मुंह से चमत्कारी ढंग से बच गए इन लोगों के मन में ऐसी वारदातों से ऑपरेशन ब्लूस्टार का खौफ हमेशा के लिए कायम हो गया.

जेल में रहने के कारण दीवान सिंह का अमृतसर का कारोबार चौपट हो गया. 1984 में उनके यहां 300 बढ़ई काम करते थे पर अब उन्हें नए सिरे से धंधे की शुरुआत के लिए मजबूर होना पड़ा है. उनका परिवार कर्ज के भारी बोझ तले दब गया है और वे अपना लकड़ी का कारोबार दो बढ़इयों को साथ लेकर किसी तरह शुरू कर पाए हैं.

उनके जेल चले जाने के कारण उनके छोटे भाई बलवंत सिंह का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया. वह जून 1985 में तत्कालीन राष्ट्रपति जैल सिंह से मिलने के लिए अमृतसर से पैदल ही दिल्ली की ओर कूच

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कर गया. उसे पक्का भरोसा था कि वह जैल सिंह से कहकर अपने भाई को छुड़वा लेगा. 15 दिनों बाद बलवंत जब राजधानी में पहुंचा तो उसे राष्ट्रपति भवन में घुसने ही नहीं दिया गया. दीवान सिंह बताते हैं, "तब से वह पूरी तरह पगला गया है."

स्वर्ण मंदिर के 30 वर्षीय सेवादार तलविंदर सिंह की तो याददाश्त ही चली गई है. उसे कुछ भी याद नहीं है, यहां तक कि अपने गांव का नाम भी नहीं. अमृतसर पुलिस उसे बाघा बॉर्डर से एक किलोमीटर दूर स्थित रोडावालां पुलिस थाने में इस उम्मीद से रखे हुए है कि किसी चमत्कार से कभी उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी.

इंदरजीत कौर का मामला सबसे अलग है. वे बड़े विचित्र हालात में सीखचों के पीछे जा पहुंची थीं. 45 महीने की नजरबंदी के दौरान वे अपने बेटे से सिर्फ दो बार मिल पाई. वे कहती हैं, "एक महीने पहले तक मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि मैं अपने बच्चों को कभी देख भी पाऊंगी या नहीं."

इंदरजीत कौर 4 जून 1984 की सुबह अपनी सहेली और पड़ोसन परमजीत कौर के साथ स्वर्ण मंदिर गई थीं. दोनों औरतें 'पाठ चालीसा' (बिना रुके गुरबानी का चालीस दिनों तक लगातार पाठ) करते हुए आधी परिक्रमा भी पूरी नहीं कर पाई थीं कि एकाएक मशीनगन की गोलियों की तडाक-तड़ाक से भोर का सन्नाटा भंग हो गया.

कोई नहीं जानता कि महिंदर कौर के बेटे का गुनाह क्या था. वे कहती हैं कि उनके पोतों को अपने पिता का चेहरा तक याद नहीं

पांच दिन बाद सेना ने जब स्वर्ण मंदिर पर अपना पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया तो यहां-वहां बिखरे शरीरों में परमजीत कौर की गोलियों से बिंधा शरीर भी पड़ा मिला. इंदरजीत कौर मरणासन्न हालत में पड़ी थीं. उन्हें अस्पताल ले जाया गया और अमृतसर के उपायुक्त के दफ्तर में सैनिक कार्रवाई के दौरान घायल हुए निर्दोष लोगों की सूची में उनका नाम दर्ज कर लिया गया.

दिसंबर 1984 में उपायुक्त ने उनसे मुआवजे के लिए आवेदन देने का आधिकारिक तौर पर निवेदन किया. जो थोड़े बहुत दस्तावेज अब भी उपलब्ध हैं उनसे पता चलता है कि सैनिक कार्रवाई में घायल हुए 59 लोगों को 10,000 से लेकर 20,000 तक का मुआवजा दिया गया. पर मुआवजा पाने वालों में इंदरजीत कौर शामिल नहीं थीं. पहले तो उन्हें अमृतसर जेल भेजा गया, फिर नाभा जेल में तबादला कर दिया गया. अंततः उनकी रवानगी जोधपुर जेल में कर दी गई.

केंद्र और राज्य सरकार के अफसर मानते हैं कि स्वर्ण मंदिर से जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनमें से ज्यादातर बेकसूर नागरिक या शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कर्मचारी ही थे. इन लोगों पर सिर्फ इसी आधार पर मुकदमे ठोंक दिए गए कि वे स्वर्ण मंदिर के भीतर उन स्थानों पर पाए गए जहां से सेना और सुरक्षा बलों पर गोलियां दागी जा रही थीं. 5 जनवरी 1985 को सीबीआई ने इन लोगों के खिलाफ जो चार्जशीट पेश की उसमें कहा गया है कि इन लोगों ने "भारत सरकार, सेना तथा अर्द्धसैनिक बलों के खिलाफ सशस्त्र मुठभेड़ में वास्तविक तौर पर हिस्सा लिया था." लेकिन प्रत्येक नजरबंद के खिलाफ न तो कोई ठोस आरोप हैं और उनके पास से हथियारों की

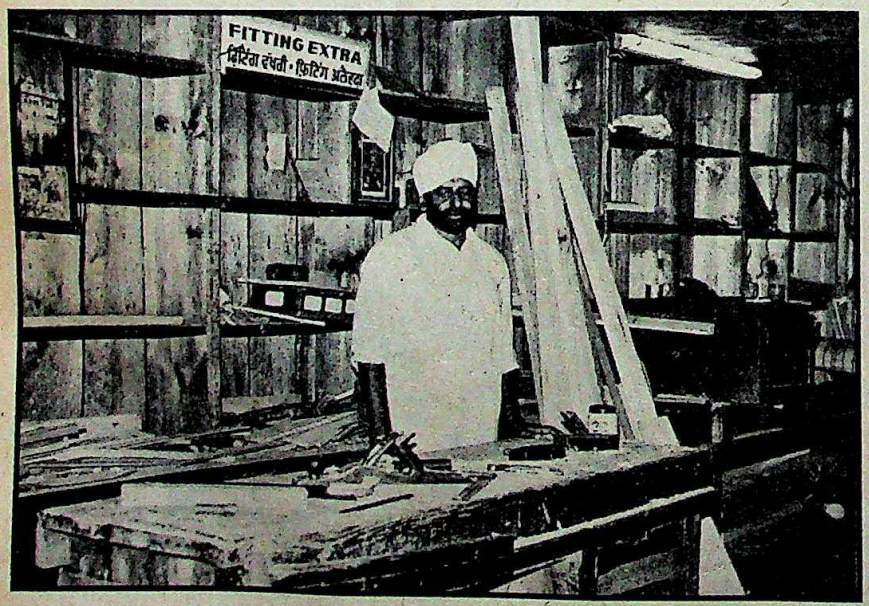

तीन सौ बढ़ई से काम करवाने वाले दीवान सिंह जेल में थे तो उनका धंधा चौपट हो गया, अब वे इसे नए सिरे से शुरू कर रहे हैं

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

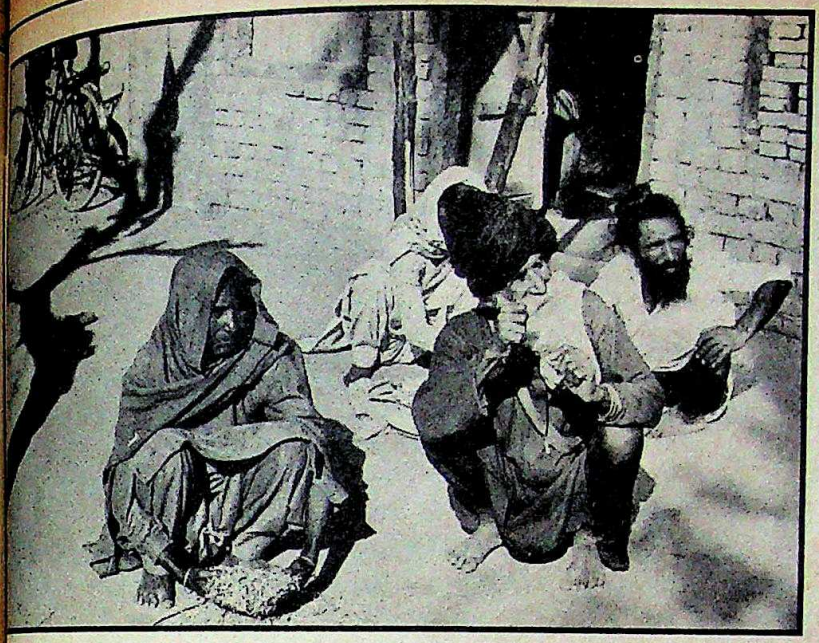

गुरुबख्श सिंह के दो किशोर बेटे अभी भी जेल में बंद हैं, जबकि वे स्वर्ण मंदिर बहुत ही कम जाया करते थे

जानकारी का कोई सबूत भी नहीं मिलता. शायद यही वजह थी कि लुधियाना की स्थानीय अदालत ने 25 बंदियों की रिहाई का आदेश दे दिया. लेकिन सीबीआई ने तुरंत ही उन सभी को 'युद्ध छेड़ने' के आरोप में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया और उनके मामले जोधपुर की विशेष अदालत के सुपुर्द कर दिए.

उनमें से एक व्यक्ति मोगा जिले के तरसेम सिंह है. स्वर्ण मंदिर से जब उन्हें पहली दफा गिरफ्तार किया गया तब उनकी उम्र 16 साल की थी. तरसेम सिंह 3 जून को मां, दो बहनों और दो भाइयों के साथ बटाला में अपनी बुआ के यहां से अपने घर लौट रहे थे. यह परिवार अपने गांव की बस पकड़ने के लिए स्वर्ण मंदिर आया. लेकिन बस को अमृतसर के बाहर नहीं जाने दिया गया. मजबूरन उन्हें स्वर्ण मंदिर लौट जाना पड़ा. ऑपरेशन ब्लूस्टार शुरू होने के बाद इस परिवार ने सेना के समक्ष समर्पण कर दिया और उन्हें लुधियाना की मॉडर्न जेल में ले जाया गया. वहां से तरसेम सिंह के अलावा परिवार को छोड़ दिया गया.

तरसेम सिंह के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. सुप्रीम कोर्ट ने लुधियाना के सेशन न्यायाधीश को निर्देश दिया कि वह जांच करे कि यह किशोर क्या किसी आपराधिक प्रकरण में लिप्त था. आखिर सितंबर 1984 में सत्र न्यायाधीश ने रिहाई का हुक्म जारी कर दिया. लेकिन साढ़े पांच महीने बाद फरवरी 1985 में सीबीआई ने इस नौजवान को फिर गिरफ्तार करके जोधपुर जेल भेज दिया. लेकिन इस बार भी उसके खिलाफ कोई खास आरोप नहीं लगाया गया.

आम धारणा यही है कि स्वर्ण मंदिर परिसर में गिरफ्तार लोग ही जोधपुर जेल में बंद हैं. लेकिन उनमें दर्जनों ऐसे ग्रामीण भी हैं जिन्हें अमृतसर शहर के बाहर, पूरे पंजाब भर से कर्फ्यू तोड़ने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था. छब्बा गांव के कश्मीर सिंह को उनके गांव के बाहर साइकिल से अमृतसर जाते हुए गिरफ्तार किया गया. वे 5 जून को जिला सत्र न्यायालय में अपने लगान संबंधी मामले की सुनवाई के लिए जा रहे थे. चूंकि उन्हें कर्फ्यू तोड़ने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया इसलिए निचली अदालत ने उन्हें रिहा कर दिया. पर तीन महीने बाद उन्हें फिर पकड़ लिया गया और उनका चालान बनाकर जोधपुर जेल में बंद कर दिया गया. कश्मीर सिंह की मां महिंदर कौर सवाल करती हैं, "क्या आप बता सकते हैं कि मेरे बेटे ने क्या जुर्म किया है?" महिंदर कौर बताती हैं कि कश्मीर सिंह के तीन बच्चों को अब तो अपने बाप की शक्ल भी याद नहीं.

अमृतसर के बाबा बकाला सब-डिवीजन में निज्जार गांव में गुरबख्श सिंह निहंग का परिवार बहुत दयनीय हालत में है. परिवार में सिर्फ दो ही पुरुष सदस्य बचे हैं: परिवार का 70 वर्षीय यह मुखिया और उनका अपाहिज बड़ा बेटा गुरदयाल सिंह. उसके दो छोटे बेटों मनजीत सिंह और गुरमीत सिंह को जब बंदी बनाकर जोधपुर भेजा गया तब उनकी उम्र क्रमशः 18 और 14 साल थी. घर-बार चलाने के लिए परिवार की औरतें पांच मील पैदल चलकर घरेलू नौकरानी का काम करने बाबा बकाला जाती हैं.

इस भूमिहीन मजहबी सिख परिवार का ऑपरेशन ब्लूस्टार से एक हफ्ते पहले एक खेत से खर-पतवार बटोरने की वजह से गांव के एक धनी जमींदार से झगड़ा हो गया था. झगड़े में परिवार के दोनों तंदुरुस्त बेटों को लाठियां लगीं और उन्हें अमृतसर के गुरु तेगबहादुर अस्पताल में भर्ती किया गया. वे 2 जून को अपने टांके खुलवाने के लिए फिर अस्पताल गए थे. 3 जून को कर्फ्यू में घंटे भर की छूट के दौरान दोनों भाइयों ने स्वर्ण मंदिर के लंगर में खाना खाने का फैसला किया. सैनिक कार्रवाई शुरू होने के बाद दोनों भाइयों ने सेना के सामने समर्पण कर दिया. गुरबख्श सिंह के पास रखे हुए अस्पताल के कागजातों और पुलिस रिपोर्टों से भी इस घटनाक्रम की ताईद होती है. इसके बावजूद अफसरशाहों और राजनैतिक नेताओं से गुरबख्श सिंह की अंतहीन अपीलें वायदों के अलावा कुछ भी नहीं हासिल कर सकीं.

पंजाब के उदारमना लोग केंद्र की घटती साख से ही चिंतित नहीं हैं, उन्हें चिंता इस बात से भी है कि वायदे पूरे न करने की उसकी राजनीति से लोग धीरे-धीरे उग्रवादी खेमों की ओर झुकने लगे हैं. अकाली दल के महासचिव मनजीत सिंह खैरा कहते हैं, "अगर उन्हें इंसाफ मिलने में बहुत देर हो जाती है तो वे उग्रवादियों के प्रति सहानुभूति रखने को मजबूर हो जाते हैं." अमृतसर पुलिस को कुछ ऐसे मामले मिले हैं जिनमें जोधपुर बंदियों के रिश्तेदार आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं. पंजाब के बड़े पुलिस अफसरों को लगता है कि यदि जोधपुर के बंदियों में से निरपराध लोगों को जल्दी ही रिहा न किया गया तो ऐसे मामले और बढ़ सकते हैं. अब तो पुलिस प्रमुख रिबेरो भी इसी विचार के कट्टर समर्थक बन गए हैं. वे कहते हैं, "मैंने इस मामले पर सर्वोच्च अधिकारियों से बात की है."

जब तक सर्वोच्च अधिकारियों को इस तथ्य का आभास होगा कि देर से न्याय मिलने का मतलब होता है न्याय का न मिलना, तब तक जोधपुर के बंदियों और पंजाब के लोगों की बेचैनी भी बढ़ती जाएगी और अंततः इंसाफ और देश के कानून पर से उनका विश्वास पूरी तरह से उठ जाएगा.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इलाहाबाद

खंदक की लड़ाई का बिगुल

इलाहाबाद में सत्तारूढ़ इंका और विपक्ष दोनों के इरादे बुलंदी पर

इलाहाबाद संसदीय सीट के लिए होने वाला उपचुनाव सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष दोनों के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है. दोनों खेमों ने प्रतिष्ठा की इस लड़ाई के लिए काफी पहले से ही अपनी-अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है. दोनों ने अपने-अपने संभावित उम्मीदवारों के नाम उछालकर मतदाताओं का दिमाग टटोलने की कोशिश की है. विपक्ष के संभावित उम्मीदवार विश्वनाथ प्रताप सिंह इस उपचुनाव को अगले साल होने वाले आम चुनाव के पहले का जनमत संग्रह मान रहे हैं. इलाहाबाद की राजनैतिक सरगर्मी पर वरिष्ठ संवाददाता ***दिलीप अवस्थी*** *की रिपोर्ट और साथ में इंडिया टुडे का जनमत सर्वेक्षण (बाक्स देखें) :*

इलाहाबाद में माहौल पहले से ही गरम होना शुरू हो गया है, हालांकि इस संसदीय सीट के उपचुनाव की तारीख की घोषणा अभी होनी है. उत्तर प्रदेश सरकार ने चुनाव आयोग से 18 मई को पड़ने वाली ईद के बाद यह उपचुनाव कराने का अनुरोध किया है. अब इस बात की पूरी उम्मीद है कि यह लड़ाई देश के भावी नेतृत्व का फैसला कर देगी. इस उपचुनाव को अंतिम जनमत संग्रह यानी अगले साल होने वाले आम चुनाव के पहले का जनमत संग्रह माना जा रहा है.

इस उपचुनाव को लेकर दांव पहले से ही ऊंचा लगा हुआ है. वी.पी. सिंह ने कांग्रेस पार्टी से निकाले जाने के बाद पहली बार अपने गृहनगर का दौरा किया. इस दौरे में चुनाव अभियान शुरू करने के सभी लक्षण मौजूद थे. बाद में एक अनौपचारिक बातचीत के दौरान उन्होंने बेहिचक कहा भी, "अमिताभ को इलाहाबाद में राजनैतिक रूप से दफना दिया जाएगा."

दूसरी तरफ इंका भी जी-जान से मोर्चा संभाले हुए है. प्रदेश के गृहमंत्री गोपीनाथ दीक्षित ने इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र के सभी नौ ब्लॉकों में पार्टी कार्यकर्ताओं की बड़ी-बड़ी बैठकें कीं. इनसे उत्साहित होकर वे कहते हैं, "यह उपचुनाव वी.पी. सिंह और विपक्ष की सारी संभावनाएं ही खत्म कर देगा."

दरअसल, इस उपचुनाव में लगे ऊंचे दांव को देखकर दोनों खेमे यह मानने लगे हैं कि यहां की मौजूदा परिस्थितियां आगे चलकर बिलकुल बदल जाएंगी. जनता पार्टी, लोकदल (अ) और (ब) और जनमोर्चा को मिलाकर बने संयुक्त विपक्ष ने पहले से ही साझा उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला कर लिया है. लेकिन उन्हें संदेह है कि सरकार चुनाव कराएगी. सिरसा बाजार की अपनी जनसभा के बाद वी.पी. सिंह ने कहा, "इस सभा से कांग्रेस को लोगों की नब्ज का पता चल गया है. अब वह यहां चुनाव कराने का साहस नहीं करेगी."

इलाहाबाद की रैली में वी.पी. सिंह: आश्वस्त

आर.के. गुप्ता

पूरी उम्मीद है कि यह लड़ाई देश के भावी नेतृत्व का फैसला कर देगी. इसे आम चुनाव के पहले का जनमत संग्रह माना जा रहा है

विपक्षी नेता और खुद वी.पी. सिंह इस तथ्य पर भरोसा कर रहे हैं कि इलाहाबाद उपचुनाव राजीव के नेतृत्व के लिए एक कड़ी परीक्षा होगी. अपनी जनसभा में अरुण नेहरू, विद्याचरण शुक्ल, और मुफ्ती मुहम्मद सईद के साथ मंच पर बैठे वी.पी. सिंह ने कहा, "इस उपचुनाव में सच और झूठ के बीच लड़ाई होगी, काले धन की बोरियों के बीच और इलाहाबाद की पवित्र भूमि के बीच लड़ाई होगी, देशभक्तों और देश के दुश्मनों के बीच लड़ाई होगी."

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इलाहाबाद में जनमत सर्वेक्षण

वी.पी. सिंह का पलड़ा भारी

पिछले साल जुलाई में अमिताभ बच्चन को लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि इस बात के सबूत सामने आ गए थे कि उनके भाई अजिताभ बच्चन के नाम पर स्विट्ज़रलैंड में एक मकान है. बोफोर्स मामला उन दिनों विवाद की बुलंदियों पर था और लोगों को लगता था कि बच्चन बंधु भी जरूर कहीं न कहीं इस घोटाले से जुड़े हुए हैं. अब हालत यह है कि संसद में पिछले आठ महीने से अमिताभ के चुनावी चेहरे—इलाहाबाद की नुमाइंदगी ही नहीं हो रही.

लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से इलाहाबाद संसदीय सीट पर जल्दी ही उपचुनाव होने की अटकलें सरगर्म हैं. अमिताभ को फिर लड़ाने की कोशिशें भी शुरू हो गई हैं. अप्रैल में राज्यसभा से वी.पी. सिंह का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है. उन पर इस बात के लिए दबाव डाला जा रहा है कि वे उपचुनाव में विपक्ष की नुमाइंदगी करें. उनके जीतने की संभावनाएं हैं यह जानने के लिए 'इंडिया टुडे' ने देश की एक अगुआ बाजार सर्वेक्षक कंपनी—मार्केटिंग ऐंड रिसर्च ब्यूरो (मार्ग) से वहां एक सर्वेक्षण कराया. 'मार्ग' के सर्वेक्षणकर्ता इलाहाबाद संसदीय सीट के तहत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में गए. कुल 612 मतदाताओं से बातचीत की, जिनमें शहरी भी थे और देहाती भी, मर्द भी थे और औरतें भी.

उनके सर्वेक्षण के नतीजे बताते हैं कि अगर इलाहाबाद में वी.पी. सिंह-अमिताभ बच्चन की टक्कर हुई तो जनमोर्चा नेता 10 फीसदी वोटों से यह लड़ाई जीत जाएंगे. यह नतीजा तकरीबन वैसा ही है जैसा जुलाई 1987 में हुए 'इंडिया टुडे' और 'मार्ग' के सर्वेक्षण में निकला था. तब वी.पी. सिंह की बढ़त 14 फीसदी थी.

औरतों में अमिताभ के प्रति झुकाव बढ़ा है (वे अब उन्हें वी.पी. सिंह के मुकाबले ज्यादा पसंद करती हैं), पर अमिताभ मर्दों में वी.पी. सिंह के मुकाबले 32 फीसदी पिछड़ गए हैं (पिछली बार यह आंकड़ा 14 फीसदी था). अमिताभ ने जहां प्रचार माध्यमों से प्रभावित होने वाले शहरी मतदाताओं में वी.पी. सिंह की तुलना में अपनी स्थिति थोड़ी सुधारी है, वहीं ग्रामीण मतदाताओं में वी.पी. सिंह की स्थिति और मजबूत हुई है. पर अमिताभ को यह जानकर शायद कुछ सुकून मिलेगा कि अगर इस दफा फिर उन्हें लोकदल प्रत्याशी बहुगुणा से भिड़ना पड़ा तो वे आसानी से जीत जाएंगे.

बोफोर्स विवाद को इलाहाबाद के लोग भूलने लग गए हैं और पिछले सर्वेक्षण के मुकाबले इसकी जानकारी रखने वालों का आंकड़ा (34 फीसदी तक) आ गया है. इस मुद्दे के बारे में औरतों की जागरूकता का स्तर 61 से 48 फीसदी तक नीचे चला आया है. जिन्हें इस विवाद की जानकारी है उनमें एक तिहाई (पहले जितने ही) यह मानते हैं कि अमिताभ इस घोटाले में शामिल थे.

राज्य में वी.पी. सिंह और उनकी पार्टी के जोरदार अभियान के बावजूद इलाहाबाद के आधे मतदाता उनके संगठन जनमोर्चा के बारे में कुछ नहीं जानते. औरतों को इसकी सबसे कम (28 फीसदी) जानकारी है. देहात के 36 फीसदी लोग ही यह जानते हैं. आखिर में इन लोगों से यह पूछा गया कि क्या वी.पी. सिंह अपनी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं. इस पर आधे लोगों ने कहा कि उनका कामकाज उम्मीद से कहीं अच्छा रहा है. और 20 फीसदी का कहना था कि उनका कामकाज उम्मीद से भी खराब रहा है.

इलाहाबाद से कौन जीतेगा

	मर्द		औरतें		कुल	
	जुलाई '87	मार्च '88	जुलाई '87	मार्च '88	जुलाई '87	मार्च '88
वी.पी. सिंह	57	66	55	43	57	55
अमिताभ बच्चन	43	34	45	57	43	45
बढ़त	14	32	10	–14	14	10
अमिताभ बच्चन	59	46	64	73	60	59
हेमवतीनंदन बहुगुणा	41	54	36	27	40	41
बढ़त	18	–8	28	46	20	18

(नहीं जानते कहने वालों के आंकड़े शामिल नहीं) (सभी आंकड़े प्रतिशत में हैं)

बोफोर्स सौदे की जानकारी

	मर्द		औरतें		कुल	
	जुलाई '87	मार्च '88	जुलाई '87	मार्च '88	जुलाई '87	मार्च '88
जानकारी है	61	48	26	20	44	34
जानकारी नहीं है	39	52	74	80	56	66
बच्चन बंधु शामिल हैं या नहीं						
हैं	41	38	31	31	38	36
नहीं हैं	23	20	18	26	22	21
कह नहीं सकते	36	42	51	43	40	43

यह सवाल सिर्फ उनसे पूछा गया जिन्हें जानकारी है

(नहीं जानते कहने वाले शामिल नहीं) (सभी आंकड़े प्रतिशत में हैं)

सभी तालिकाएं: राजीव मदान

जनमोर्चा की जानकारी
(मार्च '88)

	मर्द	औरतें	कुल	ग्रामीण	शहरी
है	59	28	43	36	55
नहीं है	41	72	57	64	45

(नहीं जानते कहने वाले शामिल नहीं) (सभी आंकड़े प्रतिशत में हैं)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पर अमिताभ की संभावित उम्मीदवारी के मुद्दे पर यहां के कांग्रेसी हलकों में तीव्र प्रतिक्रिया हुई है. इलाहाबाद के पूर्व विधायक और केंद्रीय मंत्री राजेंद्र कुमारी वाजपेयी के पुत्र अशोक वाजपेयी कहते हैं, "हमने पार्टी में असर रखने वाले हर नेता को चेतावनी दी है कि अमिताभ को फिर मैदान में न उतारा जाए वरना पार्टी के लिए यह चुनाव भारी पड़ जाएगा."

पिछली 1 फरवरी को गुलाम नबी आजाद ने अमिताभ की उम्मीदवारी के मामले पर चर्चा करने के लिए इलाहाबाद के नेताओं की दिल्ली में बैठक बुलाई थी. ग्रामीण विकासमंत्री और इलाहाबाद से विधायक श्यामसूरत उपाध्याय ने सतीश जायसवाल, रमाकांत मिश्र (दोनों यहां से विधायक) और अशोक वाजपेयी के सुर में सुर मिलाकर कहा कि अमिताभ को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए.

नगर इंका समिति के महासचिव और अमिताभ के एक चुनाव प्रभारी रह चुके यमुना प्रसाद कहते भी हैं, "यदि अमिताभ इस बार चुनाव लड़े तो राजा साहब के हाथों बुरी तरह मात खाएंगे."

राज्य के जनमोर्चा नेता वी.पी. सिंह की उम्मीदवारी के बारे में निश्चित मन नहीं बना पाए हैं. इस चुनाव क्षेत्र से दो बार चुने गए लोकदल (ब) नेता जनेश्वर मिश्र कहते हैं, "वी.पी. सिंह विपक्ष के एकमात्र पसंदीदा उम्मीदवार हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने ही इंका और उसके नेताओं में भ्रष्टाचार के खिलाफ सफलतापूर्वक जोरदार अभियान चलाया है." वी.पी. सिंह भी अपनी उम्मीदवारी के बारे में कोई वचन नहीं देते. उन्होंने कहा, "पहले वे (कांग्रेस) अपना पत्ता तो चलें. और चुनाव की घोषणा करें, तभी मैं कोई फैसला करूंगा." इलाहाबाद (उत्तर) से लोकदल (ब) विधायक अनुग्रह नारायण सिंह कहते हैं, "उनका दिल जानता है कि वही हमारे उम्मीदवार हैं." इलाहाबाद के करछना विधानसभा क्षेत्र से जनता विधायक और पूर्व मंत्री रेवती रमण सिंह ने सिरसा बाजार जनसभा में वी.पी. सिंह के बोलने के ठीक पहले लोगों से इस सिलसिले में एक सवाल किया, "आप लोगों में से कितने लोग चाहते हैं कि राजा साहब इंका के खिलाफ खड़े हों?" जवाब में सभी के हाथ ऊपर उठ गए.

विपक्ष और इस संसदीय चुनाव क्षेत्र के पांच में से तीन विधायक यदि वी.पी. सिंह का समर्थन कर रहे हैं तो इस बात की ज्यादा उम्मीद है कि चुनाव का नतीजा उनके पक्ष में जाएगा. मेजा विधानसभा क्षेत्र के विधायक विश्राम दास भी इंका से विद्रोह करके जनमोर्चा में चले आए हैं. दो कांग्रेस विधायक—सतीश जायसवाल (इलाहाबाद दक्षिण) और रमाकांत मिश्र (बाड़ा) अमिताभ की उम्मीदवारी के खिलाफ चल रहे अभियान की अगुआई कर रहे हैं. पिछले चुनाव में मात खाए लोग भी वी.पी. सिंह के साथ इलाहाबाद के सात विपक्षी विधायकों सहित सिरसा बाजार की जनसभा में मौजूद थे. अब वी.पी. सिंह के खेमे को लोकदल (ब) के बहुगुणा गुट का समर्थन लेने का मुद्दा हल करना बाकी रह गया है. सिरसा बाजार की रैली में लोकदल (ब) नेताओं की गैरमौजूदगी संदिग्ध रही. पार्टी के असरदार नेता माने जाने वाले वकील रामाधीन सिंह ने इस बारे में सफाई दी, "हमें न्योता नहीं गया था इसलिए हम

1984 में अमिताभ का चुनाव प्रचार: इस बार सफलता संदिग्ध

भवान सिंह

इंका उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए बीरबहादुर सिंह अपने मंत्रियों के साथ इलाहाबाद निर्वाचन क्षेत्र का व्यापक दौरा करेंगे

जनसभा में नहीं गए. लेकिन यदि वे हमारे पास आएंगे तो हम पूरा समर्थन देंगे."

इलाहाबाद में जैसे-जैसे चुनाव की गरमाहट बढ़ती जा रही है, मुख्यमंत्री बीर बहादुर सिंह और उनके गृहमंत्री थोड़ा चिंतित होने लगे हैं. मुख्यमंत्री ने इस संसदीय क्षेत्र के 85 न्याय पंचायतों वाले नौ ब्लॉकों में 2 और 3 अप्रैल को पदयात्रा के लिए कांग्रेस नेताओं के आठ दल बनाए हैं. हर दल का मुखिया एक मंत्री होगा. मुख्यमंत्री सिरसा बाजार से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर गोहिया में 5 अप्रैल को एक जनसभा को संबोधित करेंगे. वे इलाहाबाद हाईकोर्ट में 31 लाख रुपए की लागत वाले एक नए पुस्तकालय भवन के निर्माण का उद्घाटन करेंगे और कोहारघाट में टोंस नदी पर डेढ़ करोड़ रुपए की लागत वाले एक पुल की आधारशिला रखेंगे. सरकारी मशीनरी इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र में अब पूरी तरह सक्रिय हो गई है. पर एक स्कूटर मेकेनिक गुलाम मुर्तजा की यह टिप्पणी काबिलेगौर है. "सभी लोग जानते हैं कि इस बार इलाहाबाद देश के अगले प्रधानमंत्री का फैसला कर देगा."

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हिंदुजा की महत्वाकांक्षाएं

अशोक लेलैंड पर कब्जा जमा चुकने के बाद हिंदुजा बंधु अब संयुक्त क्षेत्र की दो विशालकाय परियोजनाओं में दिलचस्पी ले रहे हैं. पहली योजना है 1000 करोड़ रुपए वाली सलीमपुर पेट्रोकेमिकल कांप्लेक्स की. यह पहले उत्तर प्रदेश के प्रदेशीय औद्योगिक निगम को सौंपी गई थी. केंद्र सरकार चाहती है कि हिंदुजा बंधु सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड के साथ इस योजना को हाथ में लें. शुरू में रिलायंस, आदित्य बिड़ला समूह और सिंघानिया घराने ने इस योजना में दिलचस्पी दिखाई थी.

हिंदुजा बंधु टाटा घराने और सरकारी कंपनी इंडियन आयल को मिली करनाल रिफाइनरी परियोजना में भी हिस्सेदारी चाहते हैं. इस परियोजना पर काम थोड़ा आगे बढ़ा भी है. टाटा और इंडियन आयल एक संयुक्त कंपनी बनाने की तैयारी में हैं. सोवियत संघ को तकनीकी भागीदार बनाने का फैसला भी किया गया है. इसलिए हो सकता है इस मामले में हिंदुजा बंधु कुछ पिछड़ जाएं और उनके इरादे पूरे न हो पाएं.

अंबानी का 'पैशन'

अंबानी घराने द्वारा शुरू की गई विज्ञापन एजेंसी, मुद्रा कम्युनिकेशंस अब 'पैशन' नाम से कई तरह की उपभोक्ता सामग्रियां बाजार में लाने जा रही है. 28 करोड़ रुपए के कारोबार वाली अहमदाबाद की यह एजेंसी कई निर्माताओं से सामान तैयार कराके (यूरोप के फैशन हाउसों की तरह) उन्हें एक खास ब्रांड नाम से बेचा करेगी. 'पैशन' नाम से कौन-कौन चीजें बेची जाएंगी यह अभी तय नहीं हुआ है, पर उम्मीद है कि बिक्री वाली चीजों में सौंदर्य प्रसाधनों से लेकर कपड़े और चमड़े की बनी वस्तुएं होंगी.

कुशल कारीगरों पर नजर

पेट्रोलियम उद्योग के कुशल लोगों के लगातार विदेश जाने से परेशान सरकारी तेल कंपनियों ने एक नया काम शुरू किया है. बाहर जाने वाले लोग आम तौर पर अधिक कमाई की उम्मीद में पश्चिम एशियाई देशों में जाते थे. अब सरकारी कंपनियों ने पेट्रोलियम इंडिया इंटरनेशनल नामक नई कंपनी बनाई है जो कुशल कारीगरों को ठेके पर विदेशों में भेजा करेगी. ठेके की शर्तों के अनुसार काम करने गए लोगों को अपनी कमाई का एक हिस्सा इस नई संस्था को देना होगा. बदले में उन्हें विदेशों में एक देसी संस्था की सुरक्षा का लाभ मिलेगा. स्वदेश लौटने पर ये लोग अपनी मूल कंपनियों में काम पा सकेंगे. इस कंपनी ने अभी तक कुवैत, सऊदी अरब, मलेशिया और अबु धाबी जैसे कई देशों में ऐसे ठेके हासिल भी कर लिए हैं.

अब जिंसों के बाजार में

कलकत्ता की पियरलेस जनरल फाइनेंस ऐंड इन्वेस्टमेंट कंपनी भी उपभोक्ता जिंसों के लिए देशव्यापी विपणन व्यवस्था बनाने की सोच रही है. शुरुआती निवेश 25 लाख रुपए होगा और तीन करोड़ रुपए का कारोबार होने की उम्मीद है. इस योजना के तहत बड़े नगरों में डिपार्टमेंटल स्टोर खोलना और ग्रामीण इलाकों में वैन से सामान बेचना शामिल है. कंपनी को अपने एजेंटों से इस काम में मदद मिलने की उम्मीद है. इस बीच पियरलेस कंपनी बंगलूर की एक आइसक्रीम कंपनी से उसका माल कलकत्ता में बेचने का करार करने की बातचीत चला रही है.

भंडार में कमी

विदेशी मुद्रा के भंडार में कई वर्षों तक बढ़ोतरी का दौर चलने के बाद इस साल रुपए के हिसाब से देखा जाए तो इसमें भारी गिरावट आने वाली है.

पिछले वर्ष मार्च में यह भंडार 7,645 करोड़ रुपए का था जो

चार्ट: बी.के. नर्मा

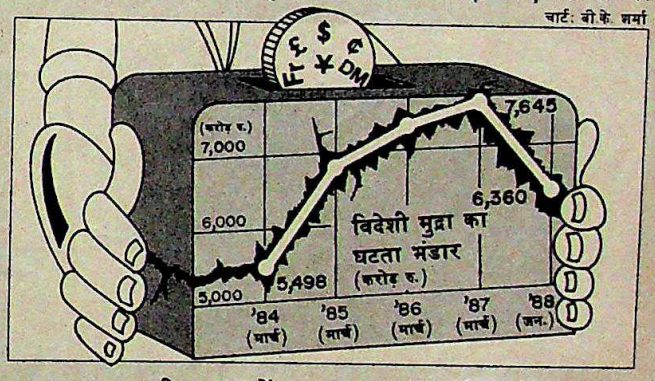

इस साल जनवरी 1988 में घटकर 6,360 करोड़ रुपए पर आ गया. रुपए के मूल्य में गिरावट को ध्यान में रखने से यह कमी और बड़ी दिखती है. अंतरराष्ट्रीय संदर्भों में मुद्रा की ताकत का असली प्रतीक 'स्पेशल ड्राइंग राइट्स' (एसडीआर) होते हैं. मार्च 1985 में 55 लाख एसडीआर का भंडार था जो पिछली जनवरी में घटकर 36 लाख एसडीआर का ही रह गया.

बदल गया इरादा

Pfizer

अमेरिकी दवा कंपनी फाइज़र द्वारा अपनी भारतीय सहयोगी कंपनी में अपने शेयर 60 से घटाकर 40 फीसदी करने के फैसले के दो वर्ष बाद अब इसे सरकारी अनुमति मिलने की उम्मीद है. पर अब अमेरिकी कंपनी का इरादा बदल गया है. वह अपने शेयर घटाना नहीं चाहती. 40 फीसदी शेयर होने से यह सहयोगी कंपनी विदेशी मुद्रा कानून (फेरा) के चंगुल से मुक्त हो जाती पर इस लाभ के बावजूद वह अपने शेयर 60 फीसदी ही रखना चाहती है.

उसका तर्क है कि फेरा के तहत आने वाली कंपनियां भी चाहें तो पिछड़े इलाकों में पूंजी निवेश कर सकती हैं. अब देखना यह है कि इस अमेरिकी कंपनी को अपनी सहायक कंपनी में शेयर घटाने की सरकारी अनुमति पहले मिलती है या यह कंपनी अपनी पिछली अर्जी वापस लेने का आग्रह ही पहले कर देती है.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सार्वजनिक क्षेत्र

अमन का लंबा दौर खत्म

कई सरकारी उपक्रमों में हड़ताल के बावजूद सरकार खामोश

औद्योगिक शांति के लंबे दौर के बाद सार्वजनिक उपक्रमों के कामगार एकदम दूसरे मूड में आ गए हैं. पिछले पखवाड़े वेतन संबंधी अपनी शिकायतें दूर न किए जाने के विरोध में देश भर के 22 लाख कामगारों ने काम रोक दिया. कोयला मजदूरों ने छह दिनों तक काम बंद रखा. इंडियन एअरलाइंस और रेलवे समेत दूसरी सभी सरकारी कंपनियों के कामगार हड़ताल पर चले गए. राजधानी में दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के ड्राइवर और कंडक्टरों ने भी हड़ताल कर दी.

हड़ताल का असर दूसरे कई उद्योगों पर भी पड़ा. जैसे बिजली और सीमेंट संयंत्र कोयले पर निर्भर करते हैं और तकरीबन हरेक उद्योग माल ढुलाई के लिए रेलवे पर आश्रित है. सरकारी अनुमान है कि हड़ताल से देश को न सिर्फ 750 करोड़ रुपए का नुकसान होगा बल्कि दिहाड़ी पर काम करने वालों को 100 करोड़ रुपए की मजदूरी से भी वंचित रहना पड़ेगा.

यह तो शुरुआत भर है. गर्मियों में मामला और गर्म होगा. केंद्र सरकार के डॉक्टर आंदोलन की राह पर हैं. यही हाल सभी सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों का है. सार्वजनिक क्षेत्र कर्मचारियों की कम-से-कम एक बड़ी यूनियन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी दी है.

निश्चित रूप से हड़ताल का दौर आ रहा है और इसका ज्यादा दोष केंद्र सरकार पर ही जाता है. सरकार ने समय से वेतन संशोधन नहीं किए, मजदूर संगठनों के साथ गंभीरता-पूर्वक बातचीत करने से इनकार किया, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से कहा कि उन पर चौथे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं हो सकतीं और डीटीसी से एकदम उलटा वायदा कर दिया.

और इस सबका नतीजा पिछले पखवाड़े विरोध के रूप में सामने आया. सरकार ने इसका उतना असर नहीं होने दिया पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की तीन दिन की हड़ताल को चुटकी बजाकर खारिज नहीं कर दिया जा सकता. जैसे उत्तर प्रदेश के 1.5 लाख में से 60 फीसदी से ज्यादा कामगारों ने काम नहीं किया. कानपुर में भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक) के लोग विरोधी मजदूर संगठनों के लोगों से भिड़ भी गए.

दिल्ली में डीटीसी की हड़ताल का निश्चित रूप से भारी असर पड़ा. 5800 बसों में से अधिकांश चलनी बंद होने से लोग पैदल, लिफ्ट लेकर, मेटाडोर, टेंपो से और जो थोड़ी बहुत बसें चलीं, उनकी छतों तक पर बैठकर अपने काम पर तथा घर पहुंचे. डीटीसी के अध्यक्ष एस.सी. वैश्य जैसे बड़े अधिकारियों को खुद कंट्रोल रूम संभालना पड़ा. आखिरकार डीटीसी को राजधानी की परिवहन व्यवस्था जैसे-तैसे चलाने के लिए करीब 2000 निजी बसें लगानी पड़ीं.

सार्वजनिक उपक्रमों में हड़ताल की जिम्मेदार केंद्र सरकार है. उसने वेतन संशोधन नहीं किए, मजदूरों से गंभीरता से बात नहीं की और चौथे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने से इनकार किया, इससे असंतोष फैला

कोयला मजदूरों की हड़ताल को असम और आंध्र प्रदेश के अलावा बहुत सफलता नहीं मिली. कोल इंडिया लिमिटेड (सीआई-एल) के एक प्रवक्ता ने दावा किया कि उसके 6.7 लाख मजदूरों में से 66 फीसदी काम पर आए और सामान्य दिनों में होने वाली लदाई का 78 फीसदी कोयला रेलवे वैगनों पर लादा गया. बिजली और इस्पात उद्योग में भी कोयले की कमी का हाहाकार नहीं मचा. प्रवक्ता का दावा था, "अगर मजदूर संघ अर्थव्यवस्था ठप करना चाहते थे, तो उन्हें असफलता ही हाथ लगी."

प्रवक्ता का कहना था कि हड़ताल का मतलब सिर्फ राजनैतिक मुद्दा उठाना था

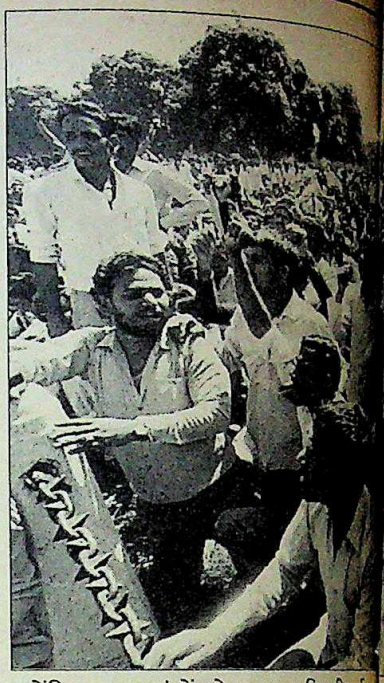

क्योंकि मजदूर संघों को पता था कि सीआई-एल के पास दो महीने का कोयला स्टॉक में पड़ा था. पर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक) के सचिव होमी दाजी ने इसका खंडन किया. एटक भी हड़ताल का आह्वान करने वालों में था. उन्होंने कहा कि सरकार कोयला मजदूरों का पिछला वेतन समझौता लागू नहीं कर रही है और इस मामले पर बातचीत करने से भी इनकार कर रही है. दाजी ने कहा, "अगर सरकार साथ बैठकर बातचीत करने को तैयार नहीं है तो हमारे पास हड़ताल ही एकमात्र हथियार बचता है."

अगर सरकार मजदूर संघों की विशेष मांगों के प्रति ऐसा रुख अपना रही है तो इससे हड़तालों का वर्तमान दौर बहुत भयावह रूप ले सकता है. ये मांगें अधिकारियों और कामगारों दोनों के लिए हैं और इनमें निम्नलिखित बातें भी शामिल हैं:

- सार्वजनिक उपक्रम के मजदूरों को 20 से 30 फीसदी तक अंतरिम राहत. एक सरकारी कमेटी ने अधिकारियों के लिए राहत की सिफारिश की है. चौथे वेतन आयोग की रिपोर्ट के बाद सरकार ने जिस तरह से केंद्रीय कर्मचारियों को मूल्य सूचकांक की पूरी क्षतिपूर्ति करनी शुरू की है, वैसी व्यवस्था मजदूरों के लिए हो.
- मजदूरों की वेतन वृद्धि की सीमा खत्म करना. अभी के नियम के अनुसार चार वर्ष के अंदर उनके वेतन में 10 फीसदी से ज्यादा की वृद्धि नहीं हो सकती.
- सरकारी इकाइयों, खासकर स्टील इंडिया लि. (एसआईएल) के निजीकरण पर रोक.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रमोद पुष्करणा

उलझा दिया है. सार्वजनिक क्षेत्र के 70 उपक्रमों के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों जितना महंगाई भत्ता मिलता है क्योंकि उन्हें उसी वर्ग से अलग करके स्वायत्त बनाया गया है. लेकिन 160 कंपनियों के कर्मचारियों को तथाकथित औद्योगिक महंगाई भत्ता (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के प्रत्येक प्वाइंट के लिए 1.65 रुपए) मिलता है. दो साल पहले सरकार ने उन 70 उपक्रमों से भी औद्योगिक महंगाई भत्ता लागू करने को कहा था पर वहां के मजदूर संघों ने मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दिया और सरकार ने इस मुद्दे को परखने के लिए एक कमेटी नियुक्त करने का प्रस्ताव रख दिया.

अब सरकारी रुख यह है कि चौथे वेतन आयोग की सिफारिशें सार्वजनिक क्षेत्र पर लागू नहीं होगी क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र में वेतनमान का संशोधन हर चार वर्ष पर हो जाता है जबकि सरकारी कर्मचारियों के वेतन का संशोधन काफी लंबे समय बाद होता है.

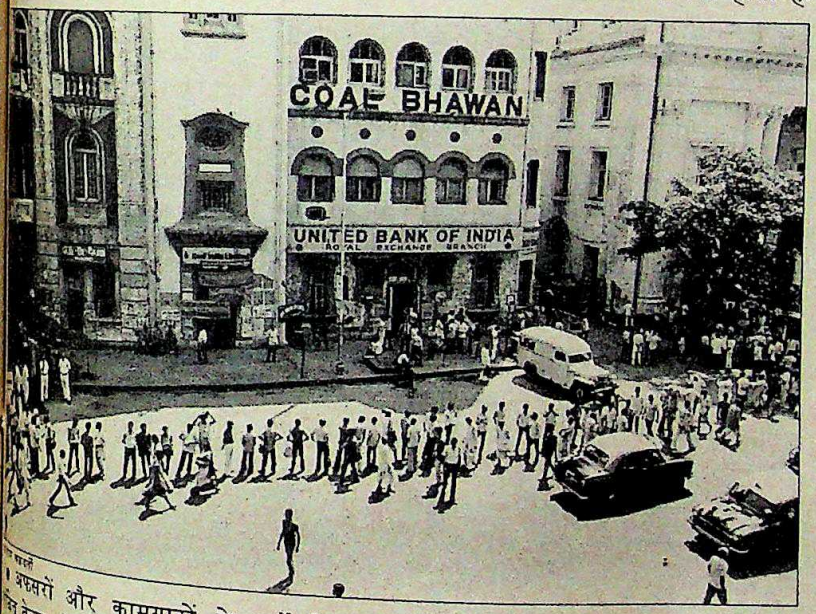

सीआईएल का कलकत्ता दफ्तर बंद करते कर्मचारी; और (ऊपर) दिल्ली के हड़ताली डीटीसी कर्मचारी

अफसरों और कामगारों के अर्से से वेतन और मजदूरी पर पुनर्विचार.

रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन और आश्रितों को नौकरी. ये मसले कोयला में खास तौर पर उठे क्योंकि पिछले में इन्हें शामिल किया गया था.

जैसे मामले सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और निजी कंपनियों के लिए हैं. इन वित्तीय मांगों को पूरा करने कितना पैसा खर्च होगा, यह भी स्पष्ट है. सरकार ने इसका हिसाब ही नहीं है. वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश मिश्र की अध्यक्षता वाली वेतन की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रही है.

इस बीच कई बातों ने मामले को और सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के अतिरिक्त सचिव सुरेश कुमार का कहना है, "अगर केंद्रीय कर्मचारियों वाला महंगाई भत्ता सार्वजनिक क्षेत्र को भी दिया जाएगा तो फिर हर चार साल पर वेतन संशोधन नहीं चल सकता. वे चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों और सार्वजनिक क्षेत्र को दी गई सुविधाओं, दोनों का लाभ एक साथ नहीं ले सकते."

इस दलील में दम तो है पर मुश्किल यह है कि सरकार खुद दोमुंहापन बरत रही है. एक से ज्यादा केंद्रीय मंत्री डीटीसी की यूनियनों को चौथे वेतन आयोग की सिफारिशें उन पर लागू करने के आश्वासन दे चुके हैं. और 70 उपक्रमों में से डीटीसी समेत कई के प्रबंधकों ने मिश्र आयोग से कहा है कि वे चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वेतन और महंगाई भत्ता देने को राजी हैं. इससे परेशान सरकार ने इन उपक्रमों के कर्ताधर्ताओं को पिछले नवंबर में बुलाकर उन पर अपनी बात वापस लेने के लिए दबाव डाला.

स्पष्ट है कि सरकार अपने फंदे में खुद फंस गई है. वह अब मजदूरों से बात न करके खुद ही आफत को न्यौता दे रही है. डीटीसी मजदूर कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन की शिकायत है कि सरकार ने डीटीसी यूनियनों से कोई बात करने से ही इनकार कर दिया. केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम अधिकारी संगठनों के राष्ट्रीय महासंघ के अध्यक्ष के. अशोक राव का कहना है कि बातचीत की उनकी अपीलों पर सरकार ने कान में तेल डाल लिया. वे कहते हैं, "अगर आप लोगों से बात करने से ही इनकार कर दें तो क्या होगा? जब मौका मिलेगा, वे जवाबी हमला करेंगे ही. और वह वक्त भी आएगा जब हम भी जवाबी हल्ला बोलेंगे." एक प्रमुख सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र यूनियन की अध्यक्षता करने वाले इंका सांसद हरीश रावत कहते हैं, "हम लोग हड़ताल की धमकी देने के आदी हो चुके हैं. उसके बाद ही फैसले लिए जाते हैं. यह अच्छी बात नहीं है."

लेकिन सरकार को चिंता तो तब होगी जब इन हड़तालों से फायदा न हो. डीटीसी को हड़ताल से रोज 10.25 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है. पर मजेदार बात यह है कि जितने दिन हड़ताल चल रही है रोज करीब उतने ही रुपए सरकार के बच भी रहे हैं जो उसे डीटीसी का सालाना घाटा भरने में लगाना पड़ता है. इसी तरह सीआईएल में एक दिन की हड़ताल से 18 करोड़ के उत्पादन का नुकसान होता है पर वेतन कटौती और गैरहाजिर कामगारों पर जुर्माने के 28 करोड़ रुपए बच भी जाएंगे. इस तरह उसे 10 करोड़ का फायदा तो होगा ही.

इन विडंबनाओं को छोड़ दें तो सरकार के लिए अभी काफी परेशानियां हैं और जब राजनैतिक माहौल इतना गर्म हो, वह सार्वजनिक क्षेत्र के 22 लाख कर्मचारियों को नाराज करने का जोखिम मोल नहीं ले सकती. चुनाव पास आते जाने से हो सकता है कि वह दबाव के आगे झुक जाए. लेकिन अभी तो वह कड़ा रुख अपनाए हुई है और उम्मीद कर रही है कि इसी से काम चल जाएगा.

—पलकुन्नथु जी. मथाई, सुरजीत दासगुप्त और दिलीप अवस्थी के साथ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

टैक्नोजर्मा

सहयोग के सूत्र

जर्मनी सहयोग बढ़ाने का इच्छुक

सभी फोटो: भवान सिंह

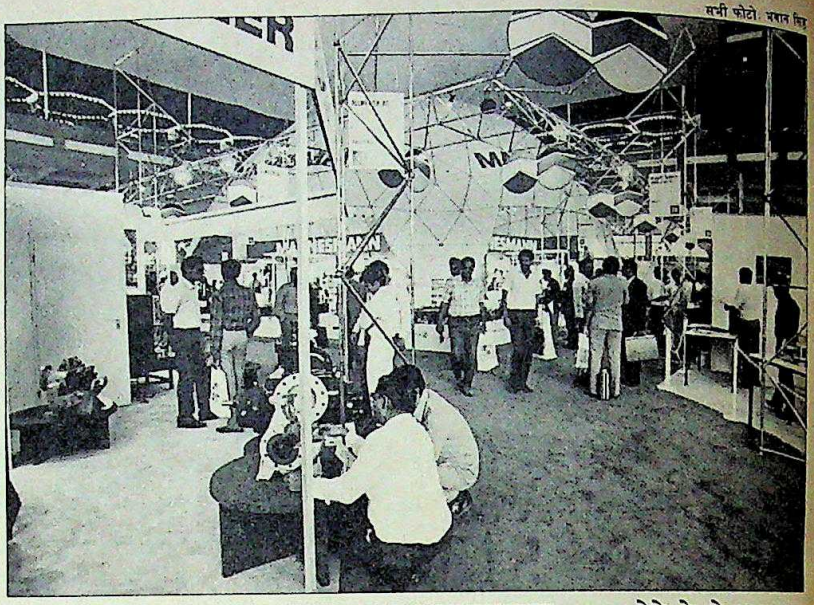

मेले के दो दृश्य: अपूर्व उत्साह

अस्सी करोड़ रुपए का यह मेला तकनीकी जानकारियों भरा और पश्चिमी जर्मनी के बाहर किसी देश में आयोजित अब तक का सबसे बड़ा मेला था. पिछले पखवाड़े पश्चिम जर्मनी ने 'टैक्नो-जर्मा इंडिया' आयोजित कर भारतीय औद्योगिक पटल पर अपनी नई तकनीकी जानकारियां रखीं.

भारत के हर कोने से आए लगभग पांच लाख दर्शकों ने पश्चिम जर्मनी की 250 से भी अधिक कंपनियों के उत्पादन देखे. इनमें सौर ऊर्जा से चलने वाली गाड़ियां, चमकीली मर्सडीज बेंज कारें, ट्रक, हल्के विमान, कंप्यूटर, लेज़र तकनीक और कंप्यूटरीकृत खराद शामिल थी.

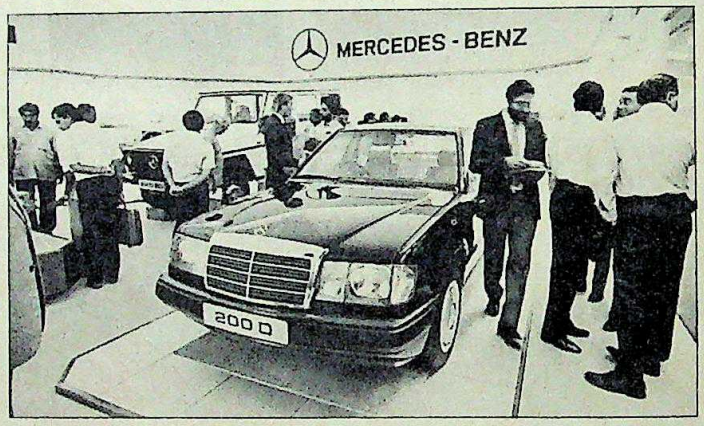

और इतना कुछ करने का फ़ायदा भी हुआ दिखता है. अभी तक पूरा हिसाब तो नहीं लगाया गया है लेकिन मेले में काफी बड़ी संख्या में व्यावसायिक सौदों के होने का अनुमान है. भारत में मशीनरी और व्यापारिक कंपनियों के समूह 'मान' के प्रतिनिधि मैनफ्रेड प्लाथ कहते हैं, "लोगों ने अप्रत्याशित रूप से इसमें रुचि दिखाई. हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि तकनीकी विवरण के बारे में पूछताछ करने वालों की संख्या एक दिन में 100 से अधिक भी हो जाएगी."

इस मेले ने जहां भारतीय व्यापारियों को तकनीक और मशीनरी प्राप्त करने का मौका दिया वहीं उन्हें अपने विदेशी सहयोगियों से मुलाकात का अवसर भी मिला. यहां तक कि जर्मन बैंक भी भारत में वित्तीय सहयोग की दौड़ में शामिल हो गए हैं.

जाहिर है कि मेले में आम उपयोग की चीजों की बजाय मशीनों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया था. टैक्नोजर्मा समिति के चेयरमैन और मेले के आयोजक हैंस गेर्ड नेग्लाइन कहते हैं, "विश्व बाजार की प्रतिद्वंद्विता में टिकने के लिए भारत को जिन पूंजीगत वस्तुओं की जरूरत है उसी पर ध्यान केंद्रित किया गया."

इसलिए मान ने अपनी नवीनतम सौर ऊर्जा तकनीक और डोर्नियर ने नवीनतम विमान प्रदर्शित किए. डायमलर बेंज की सहायक ए.ई.जी. ने मैग्नेटिक लोविटेशन ट्रांसपोर्ट सिस्टम (भारतीय रेलवे दिल्ली में जल्दी ही ऐसी व्यवस्था करने पर विचार कर रहा है) का मॉडल प्रदर्शित किया. प्रधानमंत्री राजीव गांधी जब मेले में घूम रहे थे उस समय इस मॉडल ने उनका ध्यान भी अपनी ओर खींचा था.

मेले में इतने सौदे खास जरूरतों के कारण भी हुए. पश्चिम जर्मनी की कंपनियां भारत में 183 उपक्रमों में सहयोगी हैं जबकि 1979 में यह संख्या केवल 55 थी. और अब उन्होंने भारत से सहयोग करने वालों में इंग्लैंड से दूसरा स्थान छीन लिया है. वे सहयोग की संख्या में अमेरिका के नजदीक आ गए हैं जो अभी भी 189 कंपनियों में सहयोगी बन सबसे आगे हैं. फिर भी भारत में जर्मनी की 285 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश विकासशील देशों में उसके निवेश का दो प्रतिशत से भी कम है. जर्मनी इसको बढ़ाना चाहता है.

जर्मन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार उसका निर्यात है और उसके सकल घरेलू उत्पादों में निर्यात का हिस्सा 35 प्रतिशत है. उन्हें एशिया में निर्यात की काफी संभावनाएं नजर आती हैं. भारत इसमें आधार बन सकता है. पश्चिम जर्मनी के राजदूत कोनराड ज़ाइत्स ने कहा, "हमारे लिए भारत के दो आकर्षण हैं. पूंजीगत माल की बढ़ी मांग और कुशल कारीगरों की बहुतायत." सस्ते कारीगरों का उपलब्ध होना भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है. कंप्यूटर साफ्टवेयर के मामले में भारतीय विशेषज्ञ काफी अनुभवी हैं और सीमेंस कंपनी तो भारत से उपग्रह के रास्ते इनका निर्यात करना चाह रही है. एस्कोर्ट्स के अध्यक्ष हरिप्रसाद नंदा कहते हैं, "अध्यक्ष के रूप में जो वेतन मुझे मिलता है वह प. जर्मनी की किसी कंपनी के अध्यक्ष का ड्राइवर पाता है."

जर्मन कंपनियों को भारत में तकनीकी स्थानांतरण के दौरान अपने विशेषज्ञों की फौज नहीं लानी पड़ेगी. भारत के लगभग 86 प्रतिशत संयुक्त उपक्रम बिना जर्मन विशेषज्ञों की सहायता के चल रहे हैं. देश में जर्मन विशेषज्ञों की संख्या केवल 49 है.

इन खूबियों और 'टैक्नोजर्मा' के प्रति भारतीय लोगों के रुझान ने जर्मन उद्योगपतियों को भारत का सबसे बड़ा विदेशी सहयोगी बनने की संभावनाओं की सीढ़ी दिखा दी है.

—सुरजीत बागपुर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पीथमपुर

प्रगति को पाला

इकाइयां वित्तीय संकट में

होंडा स्कूटर; छह टन के मित्सुबिशी; डायमलर बेंज लक्ज़री वैन; इसुजू इंजन वाली कार; लारसन ऐंड टुब्रो के लोडर ट्रैक्टर और केटरपिलर क्रालर ट्रैक्टर में क्या समानता है?

उत्तर: मध्य प्रदेश के आदिवासी जिले धार के एक अपरिचित से इलाके पीथमपुर में इन सभी का या तो निर्माण हो रहा है अथवा अभी निर्माण किया जाना है.

इंदौर से 35 किमी दूर 5,000 एकड़ के चट्टानी इलाके में फैला पीथमपुर का यह औद्योगिक केंद्र देश के सबसे बड़े वाहन उद्योग परिसर के रूप में तेजी से उभर रहा है. चार प्रमुख वाहन निर्माताओं ने 100 करोड़ रुपए पूंजी निवेश कर अपने कारखाने यहां खोले हैं (वैसे परिसर में कुल पूंजी निवेश 130 करोड़ रुपए है). इससे लगभग 3,000 लोगों को रोजगार मिला है. परिसर में और 260 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश अभी होना है. उसके बाद यहां रोजगार पाने वालों की तादाद 10,000 तक पहुंच सकती है. 1984 की जापान यात्रा के बाद अर्जुन सिंह ने इस परिसर की स्थापना की पुरजोर कोशिश की थी. तब उन्होंने कहा था, "पीथमपुर जल्द ही भारत का डेट्रायट (अमेरिका का ऑटोमोबाइल उद्योग केंद्र) बन जाएगा."

लेकिन लगता है अर्जुन सिंह का यह स्वप्न अब दुस्वप्न बन गया है. यहां कार्यरत चारों ही इकाइयां भारी घाटे और विशाल कर्जों के बोझ से दुहरी हो गई हैं.

अंतरराष्ट्रीय विनमय दरों में भारी उतार-चढ़ाव के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है. पीथमपुर की अमूमन सभी इकाइयां विदेशी गठबंधन से चल रही हैं. इसलिए जब भी जापानी येन और जर्मन मार्क की विनिमय दर बढ़ी, उत्पादन लागत भी बढ़ी. मित्सुबिशी के सहयोग से हलके व्यावसायिक वाहन बनाने वाली आइशर मोटर्स के वरिष्ठ अधिकारी पी.के. कापसे ने बताया, "इस वित्तीय साल के पहले छह महीनों में हमारी हालत खराब हो गई थी. लेकिन बाद के छह महीनों में तो येन ने कहर ही ढा दिया." पश्चिम जर्मनी के डायमलर बेंज के गठबंधन से चलने वाली बजाज टेंपो के वरिष्ठ अधिकारी पी.पी. जैन भी इस बात से सहमत हैं.

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा डेट्रायट बनाने के प्रलोभन और केंद्र की खुली ऑटो-मोबाइल नीति के कारण 1980 के शुरू में आधा दर्जन कंपनियां पीथमपुर पहुंच गईं. चार ने उत्पादन भी शुरू कर दिया. ये कंपनियां हैं: काइनेटिक होंडा, आइशर मोटर्स, बजाज टेंपो और हिंदुस्तान मोटर्स (यह अपने इसुजू इंजन यहां बनाती है).

ये चारों इकाइयां कई तरह की परेशानियों का सामना कर रही हैं. काइनेटिक होंडा को लोगों की पसंद बन पाने में मुश्किल हो रही है और 22 करोड़ रुपए की इस योजना में 8.5 करोड़ रुपए का घाटा पहले ही हो चुका है. कंपनी को अपने स्कूटर की कीमत 15,000 रुपए से 12,000 रुपए करनी पड़ी और अब उसने 10,000 रुपए का किफायती मॉडल भी निकाला है.

यह प्लांट अभी अपनी एक-चौथाई क्षमता (रोजाना 160 स्कूटर) पर ही चल रहा है. और मशीनरी जंग न खा जाए इसके लिए कंपनी पुर्जे जोड़कर लूना मोपेड यहीं बना रही है. और उन पर रंग-रोगन कर रही है. अपने पुणे स्थित प्लांट से वह आधा-अधूरा बना मोपेड यहां लाती है.

दूसरी ओर आइशर मोटर्स को जापानी येन की कीमत बढ़ जाने से धक्का लगा है जिससे इसकी उत्पादन लागत एकदम बढ़ गई और आइशर कैंटर की अनुमानित कीमत दो लाख रुपए हो गई है. इसका परिणाम यह हुआ है कि खरीदार नहीं मिल पा रहा. और 15 करोड़ का यह संयंत्र प्रति माह 1,000 गाड़ियों की लाइसेंस प्राप्त क्षमता की बजाय अब केवल 400 गाड़ियां ही बना रहा है.

डायमलर बेंज के सहयोग वाली 30 करोड़ की बजाज टेंपो योजना का भी यही हश्र हुआ है. पिछले तीन वर्षों में जर्मन मार्क लगभग 100 प्रतिशत चढ़ गया है, जिससे कंपनी को मुश्किल होने लगी.

हिंदुस्तान मोटर्स की योजना इसुजू इंजनों को कल-पुर्जे जोड़कर बनाने और फिर उन्हें कलकत्ता में कोंटेसा क्लासिक में लगाने की है. कंपनी की भारी-भरकम योजना थी जिसके तहत पूरी कोंटेसा का निर्माण पीथमपुर में किया जाना था. लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार और ट्रेड यूनियनों के विरोध के कारण स्थगित कर दिया गया.

इस वित्तीय संकट के दौर में नए बजट में सीमा शुल्क में छूट और विदेशी मुद्रा का रुपए में ऋण ले सकने के नए इंतजामात से कुछ आशाएं बंधी हैं. हालांकि इन व्यवस्थाओं का बाजार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका ठीक-ठीक पता नहीं है. लेकिन इस बीच उद्योगपति इस बात पर कुछ कहने की स्थिति में नहीं हैं कि क्या पीथमपुर अपने आश्वासनों के मुताबिक कभी जम पाएगा?

—नरेंद्र कुमार सिंह, पीथमपुर में

सभी फोटो: विमल गुप्ता

बजाज टेंपो की फैक्टरी

तैयार काइनेटिक होंडा

आइशर मोटर का कैंटर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

चॉकलेट बाजार

होड़ का जायका

स्थापित कंपनियों को चुनौती

देश में चॉकलेट के बाजार पर वर्षों से एक ही कंपनी का जैसे एकाधिकार रहा है. करीब 80 फीसदी बाजार पर कब्जा जमाए बैठी उस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान कोकोआ. पहले यह कैडबरी के नाम से जानी जाती थी. इसके बाद दूसरे स्थान पर है, मात्र 10 फीसदी कारोबार करने वाला गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ जो बहुप्रचारित अमूल चॉकलेट वगैरह बनाता है.

हालांकि आज 90 करोड़ के इस कारोबार में इन्हीं दोनों उत्पादकों ने पांव पसार रखे हैं लेकिन अब बाजार का जायका उतना मीठा और चुरमुरा नहीं रह गया है. बाजार में एकाएक कड़ी होड़ चल पड़ी है.

दिनोंदिन बढ़ते बाजार में कारोबार की संभावनाओं और कोकोआ के दानों के आसानी से मिलने से प्रोत्साहित होकर 'सेंट्रल एरेकानट ऐंड कोकोआ मार्केटिंग ऐंड प्रोसेसिंग कोआपरेटिव लिमिटेड' (कैंपको) जैसे नए प्रतिद्वंद्वियों ने पुराने निर्माताओं के एकाधिकार को चुनौती दी है. इस कड़ी होड़ के बीच लगभग हर कंपनी अपने विज्ञापन का बजट भी बढ़ाती जा रही है.

लेकिन लगता है कि यह गरमी अभी और बढ़ेगी. मल्होत्रा (रेजर ब्लेड वाले) को चाकलेट प्रोजेक्ट के लिए सरकारी मंजूरी मिल गई है. कंपनी के भीतरी सूत्रों के अनुसार नूडल्स और इंस्टैंट कॉफी बनाने वाली फूड स्पेशियलिटीज लिमिटेड (एफएसएल) भी इस क्षेत्र में आने वाली एक नई कंपनी के साथ साझेदारी करने पर विचार कर रही है. वैसे एफएसएल के एक प्रवक्ता ने इसे गलत बताया है. अगर वह इसमें कूद पड़ती है तो पुरानी कंपनी हिंदुस्तान कोकोआ (बिक्री: 75 करोड़ रुपए) परेशानी में पड़ सकती है.

लेकिन यह दूर की बात है. हिंदुस्तान कोकोआ को फिलहाल कई दूसरी आसन्न मुसीबतों से जूझना है. इसे 'कैंपको', पुणे की 'वेस्टर्न इंडिया चॉकलेट प्रोडक्ट्स' और एक पुराने प्रतिद्वंद्वी बंबई की 'डॉ. राइटर्स' से धीरे-धीरे चुनौती मिलने लगी है. डॉ. राइटर्स ने अपने पुराने चॉकलेट की एक सस्ती किस्म अभी बाजार में उतारी है.

वैसे, मुख्य चुनौती मंगलूर की 'कैंपको' ही दे ही है. इसने प्रतिस्पर्द्धियों के मुकाबले 25 फीसदी कम दाम पर चॉकलेट की तीन किस्में बाजार में भेजी हैं. कैंपको के विपणन सलाहकार आर. अरुणाचलम बताते हैं, "प्रतिस्पर्द्धा में कीमत की दृष्टि से हम बेहतर स्थिति में हैं." यह सहकारी संस्था (चॉकलेट की बिक्री: 6 करोड़ रुपए) खुदरा विक्रेताओं को 15 फीसदी बिक्री कमीशन (हिंदुस्तान कोकोआ से दो फीसदी अधिक) और बिक्री बढ़ाने के लिए 1 फीसदी अतिरिक्त कमीशन दे रही है. इसने कैडबरी को इसके गढ़-पश्चिमी क्षेत्र में ही सीधी चुनौती देने के बजाय दक्षिण और उत्तर के बाजार पर ही ध्यान देने का निश्चय किया है.

इस बीच स्विट्जरलैंड की एक कंपनी के तकनीकी सहयोग से चॉकलेट बनाने वाली 'डॉ. राइटर्स' को अब लगने लगा है कि सब कुछ ठीकठाक नहीं चल रहा है. इसलिए पिछले साल के अंत तक इसने अपने पुराने चॉकलेट की एक छोटी किस्म को 1 रु. की कीमत पर बाजार में उतारा. डॉ. राइटर्स के प्रबंध निदेशक वी.एम. आप्टे खुश होकर कहते हैं, "एक रुपए कीमत रखने से इसकी बिक्री बेहिसाब बढ़ी है. शहर में उपलब्ध दूसरे सभी चाकलेटों से यह सस्ता जो है."

इस तरह की जोड़तोड़ के नतीजे अच्छे भी निकले हैं. 'कैंपको' का दावा है कि देश भर के करीब 8 फीसदी बाजार पर उसने दखल कर लिया है. लेकिन एक सर्वेक्षण के अनुसार यह आंकड़ा 5 फीसदी है. कैंपको का दावा यह भी है कि दक्षिण के 25 फीसदी बाजार पर उसने कब्जा कर लिया है. यहां तक कि डॉ. राइटर्स (चॉकलेट की बिक्री: 1 करोड़ रुपए) ने भी बंबई में अच्छा बाजार बना लिया है और कुल शहरी बाजार के 5 फीसदी पर दखल जमा लिया है. कैंपको और राइटर्स ने इस वर्ष भी महत्वाकांक्षी लक्ष्य ही अपने सामने रखा है: राष्ट्रीय बाजार के क्रमश: 20 और 12 फीसदी में हिस्सेदारी का. लेकिन हिंदुस्तान कोकोआ के अध्यक्ष इन आंकड़ों को एकदम ही नकारते हैं, "प्रतिस्पर्द्धा का हम पर बहुत थोड़ा ही असर हुआ है. इतना तो होता ही क्योंकि पहली मार तो स्थापित ब्रांड पर ही पड़ती है." पिछले साल कैंपको के बाजार में आते ही हिंदुस्तान कोकोआ ने 'मॉडवैट' के तहत मिली छूट के आधार पर चॉकलेट की कीमत कम कर दी.

बहरहाल, चॉकलेट के कारोबार में इस तमाम हो-हल्ले और होड़ का एक फायदेमंद पहलू भी है. कड़ी प्रतिस्पर्द्धा के चलते उत्पादकों को नए ग्रामीण बाजारों की ओर बढ़ने की जरूरत पड़ रही है. हिंदुस्तान कोकोआ के मौजूदा कारखाने तो पूरी क्षमता से उत्पादन कर रहे हैं, अब मध्य प्रदेश में एक नया कारखाना लगाया जा रहा है. यानी चॉकलेट के और भी जायकेदार होने की संभावनाएं हैं.

—सुरजीत बालसुब्रह्मण्यन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शेयर बाजार

मानसून के भरोसे

शेयरों की कीमत और घटी

ऐसा लगता नहीं कि किसी बात से शेयर बाजार को भरोसा मिल पाएगा. केंद्रीय बजट और बाद की सरकारी घोषणाओं से लग रहा था कि उद्योग जगत के कुछ हलकों की स्थिति सुधरेगी. लेकिन पिछले पखवाड़े शेयर बाजार की गिरावट देखकर नहीं लगा कि इसे किसी तरह थामा जा सकता है. 11 मार्च का इकॉनामिक टाइम्स शेयर मूल्य सूचकांक 240.8 पर था और 23 मार्च को यह 222.9 पर आ गया. जनवरी में यह 265 के आसपास था और दो महीनों से कुछ अधिक समय में ही 12 फीसदी की गिरावट आ गई है.

शेयरों की बिक्री बढ़ना और कीमतों में गिरावट की वजह वित्त वर्ष के आखिर में संपत्ति कर के बोझ को निबटाना भी हो सकती है. लेकिन थोड़ी-सी तेजी के बाद भारी गिरावट एकदम अलग संकेत देती है.

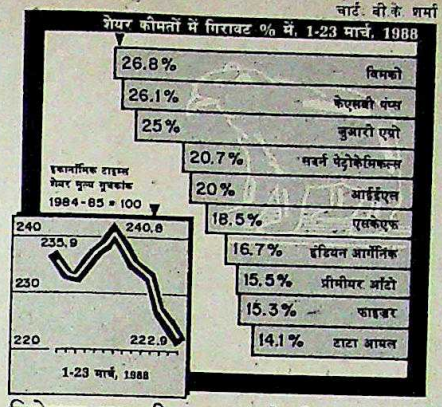

चार्ट: बी.के. शर्मा

निवेशक अब भी इस बात के लिए बेचैन हैं कि किसी तरह कुछ ज्यादा कीमत लेकर वे अपने शेयरों से पिंड छुड़ा लें. स्पष्ट है कि बाजार में जान फूंकने के लिए निवेशकों का जो भरोसा होना चाहिए, वही गायब है.

बाजार में पुनर्व्यवस्था कायम होने का मसला काफी समय से रुका पड़ा है. विभिन्न जिंसों की कीमत बढ़ाने और रियायतें देने से कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा. अनेक कंपनियां अपने बेहतर छमाही कामकाज की रिपोर्ट भी जारी कर रही हैं. तब भी अनेक शेयर अपनी मूल कीमत के आसपास आ गए हैं. माल ढोने की दर दुनिया भर में बढ़ने के कारण नौपरिवहन कंपनियों की हालत भी सुधरने की उम्मीद है. ऐसे में भी बाजार की दुर्गति होने से सारे विशेषज्ञ चकराए हुए हैं. उनमें से कुछ का मानना है कि यह शेयर बाजार का अपना खास ढुलमुलाना है.

शेयरों के मूल्यों में गिरावट को गौर से देखने पर लगता है कि इस पखवाड़े सबसे अधिक नुकसान उठाने वाले शेयर परेशानी में पड़ी रासायनिक खाद कंपनियों के हैं. इनमें जुआरी, सदर्न पेट्रोकेमिकल्स और आईइएल शामिल है. मुश्किल में पड़े पोलिएस्टर स्टेपल फाइबर प्लांट वाली इंडियन आर्गेनिक कंपनी के शेयर भी काफी नीचे गिरे. दवा के मूल्यों में बढ़ोतरी और बजट से फायदे मिलने के बावजूद प्रसिद्ध दवा कंपनी फाइजर के शेयर भी गिरे.

दूसरी ओर सेंचुरी एंका (जिसने बढ़िया कामकाज किया है) और टाटा समूह की दोनों बड़ी कंपनियों के शेयर चमके. इन दोनों के बेहतर कामकाज की रिपोर्ट आने की संभावना है. रिलायंस भी कुछ चमका.

इसलिए अब लगता है कि बाजार में अच्छे मानसून के बिना ज्यादा उफान आने की उम्मीद नहीं है. हां, इस बीच वह थोड़ा-बहुत ऊपर चढ़ सकता है. लेकिन अभी की स्थिति में कुछ भी तेजी स्वागतयोग्य है.

जमा स्टॉक

	1988 ऊंचा	1988 नीचा	1988 बंद 21.3.88	पखवाड़े में स्टॉक की स्थिति
[illegible]	36.50	30.50	32.50	0.50 +
[illegible] सोमेंट	180.00	137.00	142.00	2.00 +
[illegible]	63.50	38.00	38.00	2.00 —
[illegible]	169.00	140.00	140.00	8.75 —
[illegible]	520.00	383.00	407.50	7.50 —
[illegible]	185.00	140.00	172.00	12.00 +
[illegible]	71.50	55.00	55.00	3.50 —
[illegible]	320.00	280.00	310.00	20.00 +
[illegible]	126.50	101.00	122.00	3.00 +
[illegible]	44.00	33.00	34.00	4.00 —
[illegible]	125.00	45.00	48.00	6.50 —
[illegible]	138.00	94.00	128.00	4.50 +
[illegible]	87.00	75.00	83.00	4.25 +
[illegible]	109.00	84.00	89.00	0.50 —
[illegible]	88.00	75.00	81.25	—
[illegible]	1660.00	1080.00	1480.00	55.00 +
[illegible]	80.50	66.00	67.50	3.50 —
[illegible]	74.00	61.00	65.00	1.00 —
[illegible]	220.00	173.75	176.25	16.00 —
[illegible]	38.25	28.00	31.00	1.50 +
[illegible]	83.00	71.00	77.50	3.25 +
[illegible]	44.00	38.00	38.00	1.00 —
[illegible]	380.00	300.00	323.75	8.75 +
[illegible]	142.00	95.00	96.25	10.00 —
[illegible]	37.00	20.00	33.00	3.00 +
[illegible]	26.35	20.50	23.85	1.00 +
[illegible]	118.00	86.50	96.00	3.00 —
[illegible]	104.75	83.50	86.25	0.75 +
[illegible]	139.00	116.00	124.00	3.00 +
[illegible]	215.00	72.50	78.75	1.25 —
[illegible]	81.00	62.50	65.00	2.00 —
[illegible]	25.00	16.80	16.80	1.10 —
[illegible]	212.50	140.00	141.25	7.50 —
[illegible]	43.75	33.00	33.50	4.00 —
[illegible]	120.50	100.00	102.50	—

	1988 ऊंचा	1988 नीचा	1988 बंद 21.3.88	पखवाड़े में स्टॉक की स्थिति
इंडियन आर्गेनिक	23.00	15.00	15.50	2.00 —
इंडियन रेयॅन	58.00	46.00	50.00	1.00 +
इंड्राल	223.75	152.50	152.50	13.75 —
इंगरसॉल-रैंड	335.00	250.00	250.00	12.50 —
आई.टी.सी.	39.75	30.00	35.00	3.00 +
जे.के. सिंथेटिक्स	69.00	48.00	57.50	2.50 +
काइनेटिक इंजी.	200.00	161.25	177.50	2.50 +
किर्लोस्कर क्युमिंस	57.50	48.00	53.75	3.75 —
केएसबी पम्प	425.00	252.50	260.00	60.00 —
लारसन-टुब्रो	95.50	75.50	82.00	4.00 +
लिप्टन	67.00	52.00	58.00	2.00 +
लोहिया-मशीन्स	13.50	9.00	10.50	0.50 +
महिंद्रा-महिंद्रा	63.00	51.50	52.00	3.00 —
मैक्डोवेल	83.50	72.00	78.00	6.00 +
मोटर इंडस्ट्रीज	587.50	490.00	500.00	5.00 —
मुकुंद आयरन	85.00	72.50	78.50	—
नेशनल आर्गेनिक	525.00	402.50	402.50	23.00 —
निरलॉन	8.75	5.00	7.50	0.50 +
ओरके सिल्क मिल्स	30.00	17.50	19.00	2.50 —
पेइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स	33.75	25.75	25.75	1.75 —
ओसवाल आग्रो	134.50	58.00	58.00	28.62 —
ओटिस एलिवेटर	215.00	180.00	186.00	1.00 +
प्रीमियर ऑटो	31.00	23.00	24.50	0.50 —
रैनबेक्सी	102.50	76.00	82.60	3.50 +
रेमंड	96.00	44.00	45.00	2.50 —
शॉ वैलेस	132.00	56.00	56.00	3.00 —
रिलायंस इंडस्ट्रीज	117.00	81.00	83.00	1.00 +
रिचर्डसन हिंद	305.00	260.00	282.50	5.00 +
श्रीराम फाइबर्स	42.75	32.50	36.50	2.00 +
एसकेएफ बैयरिंग	1365.00	1058.00	1210.00	30.00 —
सीमेन्स इंडिया	80.00	62.00	62.00	3.00 —
स्पिक	37.00	24.00	24.00	3.25 —
टाटा स्टील	685.00	568.75	630.00	36.25 +
टेल्को	406.00	340.00	385.00	40.00 +
विम्को	24.00	15.50	15.50	4.50 —

भारतीय रुपए का मूल्य

देश	मुद्रा	इकाई	बिक्री मूल्य (रुपए में)	क्रय मूल्य (रुपए में)
आस्ट्रेलिया	डालर	1	9.7055	9.6014
आस्ट्रिया	शिलिंग	1	1.1032	1.0914
बहरीन	दीनार	1	34.3230	34.1139
बांग्लादेश	टका	100	41.6232	41.4910
कनाडा	डालर	1	10.5246	10.4163
डेनमार्क	क्रोनर	1	2.0216	2.0001
मिस्र	पौंड	1	9.3682	9.1798
फ्रांस	फ्रैंक	1	2.3255	2.2722
हांगकांग	डालर	1	1.6848	1.6679
इंडोनेशिया	रुपिया	100	0.0783	0.0699
ईरान	रियाल	100	19.4132	19.2910
इटली	लीरा	100	1.0529	1.0000
जापान	येन	100	10.4000	10.1500
केन्या	शिलिंग	1	0.7630	0.7132
कुवैत	दीनार	1	47.2932	47.1536
मलेशिया	डालर	1	5.0949	5.0387
मारीशस	रुपया	1	1.0380	1.0000
नेपाल	रुपया	1	0.6230	0.5931
हालैंड	गिल्डर	1	6.9030	6.8311
पाकिस्तान	रुपया	1	0.7281	0.6930
सिंगापुर	डालर	1	6.5210	6.4405
स्पेन	पेसो	1	0.1060	0.0912
श्रीलंका	रुपया	1	0.4093	0.3992
स्वीडन	क्रोनर	1	2.1962	2.1726
स्विट्जरलैंड	स्विस फ्रैंक	1	9.3656	9.2663
तंजानिया	शिलिंग	1	0.1491	0.1132
थाईलैंड	बहत्त	100	51.4232	50.9180
ब्रिटेन	पौंड	1	23.9740	23.8400
सं. राज्य अमेरिका	डालर	1	13.1400	13.0100
सं. अरब अमीरात	दिरहाम	1	3.5210	3.4930
सोवियत संघ	रूबल	1	22.5621	22.4131
पश्चिम जर्मनी	जर्मन मार्क	1	7.9051	7.7101

स्रोत—बैंक ऑफ टोक्यो, नई दिल्ली, 21.3.88

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बूझी पानी की पहेली

जब पानी की ज्यादा तंगी हो तो कोई सहज समाधान सूझे नहीं सूझता. नलकूपों की खुदाई से पानी का स्तर नीचे जाने का खतरा रहता है, तो इंद्र देवता के भरोसे बैठे रहना भी कोई अक्लमंदी नहीं. सो केंद्र ने नलकूपों के अलावा दो वर्षों में एक लाख गांवों को पेयजल मुहैया कराने की 250 करोड़ रुपए की योजना के तहत नई मशीनों का निर्माण किया है. इन्हें 'वाटर मशीन' कहा जाता है. इस 29 फरवरी को प्रधानमंत्री के तकनीकी सलाहकार सैम पित्रोदा ने हैदराबाद स्थित भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की प्रयोगशाला में तैयार ऐसे पहले चलते-फिरते बिलवणीकरण संयंत्र को हरी झंडी दिखाई. यह संयंत्र एक बड़ी मोटरगाड़ी में लगा है जो पानी से नमक की मात्रा को अलग कर डालता है.

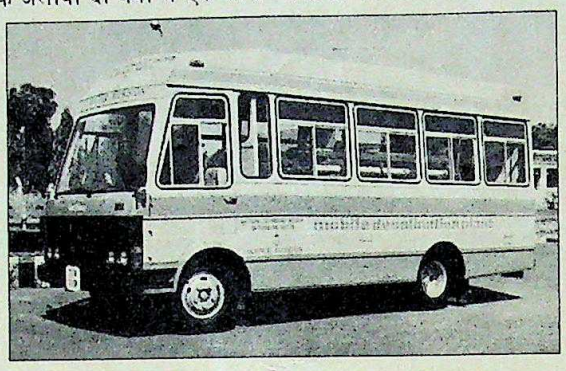

चलते-फिरते बिलवणीकरण संयंत्रः अपूर्व पहल

इस संयंत्र से बहुत से गांवों की प्यास बुझाई जा सकेगी. विशेषकर समुद्र के तटवर्ती गांवों की, जहां खारे पानी को शुद्ध करके पीने योग्य बनाया जाएगा. वैज्ञानिकों का कहना है कि विलवणीकरण की विधि सस्ती, सरल और भरोसेमंद है. यह विधि पहले भावनगर (गुजरात) के केंद्रीय लवण और समुद्र रसायन शोध संस्थान द्वारा विकसित की गई थी. लेकिन 'भेल' के इंजीनियरों ने बड़े पैमाने पर सर्पिल आकार की सेलुलोज ऐसिटेट से निर्मित झिल्लियां तैयार करने की मशीन बनाई. इन्हीं झिल्लियों से पानी साफ किया जाता है.

'भेल' के शोध और विकास विभाग के महाप्रबंधक कमलेश लाहिड़ी बताते हैं, "यह सब हमने केवल नौ महीनों में कर दिखाया." उनका कहना है कि इन संयंत्रों से रसायन उद्योग के लिए शुद्ध जल भी मुहैया कराया जा सकेगा.

'भेल' पहले ही तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गुजरात में 50,000 लिटर जल प्रतिदिन शुद्ध करने की क्षमता वाले तीन संयंत्र लगाकर इस तकनीक की सार्थकता साबित कर चुका है. मार्च के अंत तक 15,000 लिटर जल प्रतिदिन शुद्ध करने वाले छह प्रस्तावित संयंत्रों में से चार के चालू होने और वर्ष के अंत तक समुद्र के तटवर्ती गांवों में 30,000 लिटर क्षमता वाले 20 संयंत्रों की स्थापना के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि पानी की समस्या सुलझ जाएगी.

दूरदर्शी योजना

● देश भर के नौ तारामंडलों में से एक— हैदराबाद के बिड़ला तारामंडल ने अपने सामने एक नेक मकसद रखा है. कुल 27 महीने पहले खुला यह तारामंडल अब तक

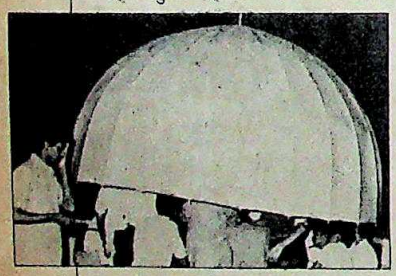

तारों को निहारना अब और आसान हो जाएगा!

दस लाख दर्शकों को आकाश के अनबूझे रहस्य दिखा चुका है. लेकिन अधिकारी इसीसे शायद संतुष्ट नहीं हैं सो उन्होंने खगोल विज्ञान का आरंभिक ज्ञान देने का निश्चय किया है. स्कूली बच्चों को व्याख्यानों, फिल्म, कार्य-सत्र, कंप्यूटर ग्राफिक्स द्वारा अंतरिक्ष के रहस्य बताये जाएंगे. तारामंडल के 39 वर्षीय निदेशक डा. बी.जी. सिद्धार्थ बताते हैं कि दिन भर के इस प्रशिक्षण में रात के आकाश, चांद की कलाओं, सौरमंडल, सितारों के इतिहास, कृष्ण विवर (ब्लैक होल्स) और ब्रह्मांड के सिद्धांतों के बारे में बताया जाएगा. बच्चों को यह प्रशिक्षण गर्मियों की छुट्टी में स्कूल बंद होने के दौरान कराया जाएगा.

इस दौरान विज्ञान संग्रहालयों की राष्ट्रीय परिषद ने छोटे आकार के तारामंडल भी बिक्री के लिए तैयार किए हैं. इनकी कीमत 60,000 रुपए होगी.

सरस्वती की साधना

● 63 वर्षीय विमल घोष अर्से से गुम हो चुकी नदी सरस्वती को खोजने के अभियान में जुटे हुए हैं. महाभारत और ऋग्वेद में उल्लिखित इस नदी का हालांकि पिछले एक हजार वर्ष से कहीं कोई चिन्ह नहीं मिला है लेकिन जोधपुर के केंद्रीय निर्जल क्षेत्र शोध संस्थान से रिटायर हो चुके ये भू-आकृतिज्ञ नदियों के लुप्त होने की बात कबूल करने को तैयार नहीं. प्राचीन ग्रंथों के संकेतों और हवाई जहाज से लिए चित्रों के आधार पर वे सरस्वती का बहाव खोजने में जुटे हैं.

हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों से निकलकर यह नदी हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से होकर बहती थी. घोष का अनुमान है कि सरस्वती के पश्चिम की ओर रुख मोड़ने और बाद में भूमिगत हो जाने के कारण ही थार का मरुस्थल बना.

घोष का यह भी अनुमान है कि जमीन की सतह के नीचे नदी के अवशेष के रूप में बचे जलमार्गों से अब भी हिमालय से पिघली बर्फ का पानी बह रहा है. सरकारी एजेंसियों ने भी इसकी आंशिक रूप से पुष्टि की है. घोष द्वारा तैयार नक्शों के आधार पर जैसलमेर में 36 नलकूप खोदे गए और आश्चर्य की बात यह है कि ये नलकूप एक घंटे में 2,000 से 4,000 लिटर पानी प्रति घंटा उलीच रहे हैं. घोष, अब यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कि थार के मरुस्थल को हरा-भरा बनाने में इस लुप्त नदी का क्या योगदान रहता. इसके अलावा घोष कच्चे तेल की तलाश के लिए नदी-मुखों के नक्शे भी तैयार कर रहे हैं.

ब्रह्मांड का रहस्य खोजेंगे

● सवाल पुराना ही है. आखिरकार प्रकृति का निर्माण किन कणों से हुआ है? भौतिकीविद और ब्रह्मांड वैज्ञानिकों का मानना है कि पदार्थ की दूसरी अवस्था 'क्वार्क ग्लूओन प्लाज्मा' (क्यूजीपी) में इसका जवाब मिल सकता है.

उनका मत है कि 15 अरब साल पहले जब एक 'बड़े धमाके' के बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, उस समय के शुरुआती क्षणों में क्यूजीपी के निर्माण के लिए बड़ी माकूल परिस्थितियां थीं.

इस रहस्य से पर्दा उठाने में जुटे वैज्ञानिकों ने परमाणु विखंडक की मदद से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के तुरत बाद की परिस्थितियां पैदा कीं. वैज्ञानिक इस परमाणु विखंडक को त्वरक कहते हैं. इसमें परमाणु के मूलभूत कण उच्च ऊर्जा पर एक दूसरे से टकराए जाते हैं. भारतीय वैज्ञानिकों ने इस प्रयोग के लिए दूसरी अपेक्षाकृत सस्ती व्यवस्था— 'वेरिएबिल एनर्जी साइक्लोट्रोन सेंटर' (वीइसीसी) की स्थापना कलकत्ता में कर ली है.

हाल ही में 14 देशों के क्यूजीपी पर किए गए अपने शोध कार्य पर विचार विमर्श के लिए

क्यूजीपी सम्मेलन में वैज्ञानिक

वैज्ञानिक बंबई में इकट्ठा हुए और उन्होंने शोध की सुविधाओं को मिल-बांटकर उपयोग करने का फैसला किया. भारत जेनेवा स्थित यूरोप की परमाणु अनुसंधान केंद्र प्रयोगशाला और अमेरिका की फर्मी नेशनल एक्सीलेटर लेबोरेटरी का सहयोग लेगा.

—अमरनाथ के. मेनन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बंबई

जंगल में अमंगल

संजय गांधी उद्यान में आबादी के बढ़ते दबाव से तेंदुए खफा

एक साल में यह चौथा हादसा था. 13 मार्च को बंबई के बोरीवली इलाके के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में चार वर्षीय रेखा जब सो रही थी तो एक तेंदुए ने उस पर हमला बोल दिया. उसकी दर्दनाक मौत ने एक बार फिर मानवीय अतिक्रमण की गंभीर समस्या को उजागर किया.

बीच टकराव कम करने की जिम्मेदारी आदमी की ही है." वे मानते हैं कि जंगलों में मनुष्यों के अतिक्रमण की रोकथाम से ही इस समस्या का कोई हल निकल सकता है. दूसरा समाधान यह है कि तेंदुओं को ही पार्क से हटा दिया जाए. लेकिन इससे वहां का पारिस्थितिक संतुलन बिगड़

दिव्यभानु सिंह/सैंक्चुअरी

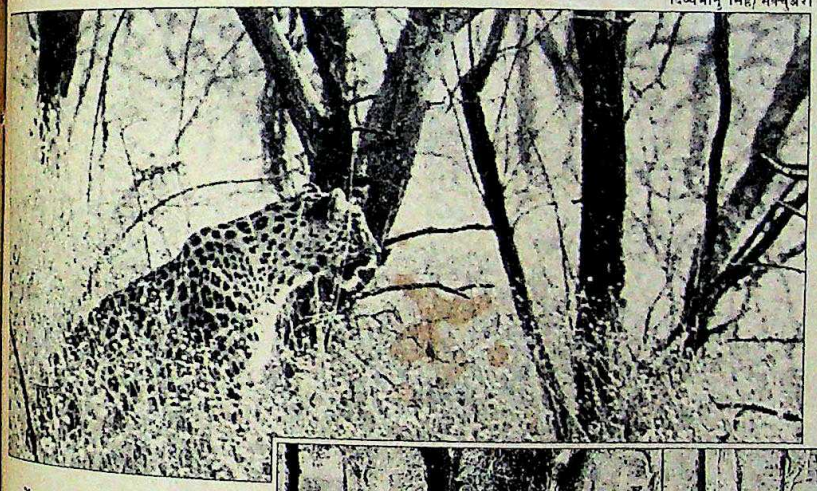

तेंदुआ (ऊपर); और जनजातीय आबादी का बसेरा: उद्यान पर बोझ

सलिल त्रिपाठी

रेखा कुणबी जनजाति की थी. इन लोगों की 18 झोंपड़ियां तेंदुओं के इलाके के ठीक बीचोबीच है. ऐसी तीन मौतें यहां पहले भी हो चुकी हैं. इनके शिकार तीन से पांच साल के बच्चे ही हुए थे. और हमलों का वक्त भी कुछ का ही था, जब वे गहरी नींद में थे. बोरीवली उद्यान में 30 तेंदुए हैं जो वन अधिकारियों के अनुसार अपने आपको हर परिस्थिति में ढाल सकते हैं. इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि ये जंगल में घुस आने वाले कुत्तों, गायों और बकरियों का शिकार करने लगे हैं.

वन संरक्षक और 'सैंक्चुअरी' नामक पत्रिका के संपादक बिट्टू सहगल कहते हैं, किसी तेंदुए को यह नहीं बताया जा सकता कि फला-फलां धारा के तहत वह मनुष्य को नहीं मार सकता. आदमी और जानवरों के

जाएगा क्योंकि घास-पात चरने वाले जानवर अधिक हो जाएंगे. उनके हरियाली चट कर जाने से रेतीले इलाके में बढ़ोतरी हो जाएगी. इसका हश्र यह होगा कि बंबई को 2.25 करोड़ गैलन पानी की आपूर्ति करने वाली विहार और तुलसी झीलें (उद्यान में ही स्थित) सूखने लगेंगी.

103 वर्ग किमी में फैले बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान पर अंदरूनी और बाहरी दोनों ओर से बढ़ती आबादी का दबाव है. तेंदुओं से सबसे ज्यादा खतरा तो 32 बस्तियों में फैले और जंगल के बीचोबीच रह रहे 500 लोगों को है. हालांकि उन्हें पश्चिमी इलाके के गांव मालवणी में बसाने का प्रस्ताव है लेकिन राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए जाने के बहुत पहले से यहां रह रहे लोगों को कहीं और बसाना टेढ़ी खीर ही है. वर्तमान कानून में संशोधन के बिना उन्हें जबरदस्ती हटाया नहीं जा सकता. लेकिन हाल ही में तेंदुओं के हमलों ने उद्यान में बसने वालों को भयभीत कर दिया है. पिछले कुछ वर्षों में उद्यान के पश्चिमी किनारे पर डिंदोशी जैसी कई झोंपड़पट्टियां बस गई हैं. जंगल के नजदीक ही ओटिस एलीवेटर्स, महिंद्रा ऐंड महिंद्रा और कुछ दवा कंपनियों ने कारखाने डाल लिए हैं.

उद्यान के मंडलीय प्रबंधक एस.डी. साठे कहते हैं, "उद्यान का एक इंच भी इलाका प्रदूषित होने से नहीं बचा है. हमारा वक्त तो फेंकी गई जलती सिगरेटों से लगी आग बुझाने में ही निकल जाता है." उनका प्रस्ताव है कि लोगों की आम आवाजाही रोकने के लिए एक पक्की दीवार बना दी जानी चाहिए. लेकिन इस पर लगभग 7 करोड़ रुपए खर्च आएगा जबकि उद्यान का सालाना बजट 70 लाख रुपए का ही है.

लेकिन सभी प्रस्ताव उद्यान के हित को ध्यान में रखकर नहीं रखे जाते. इसी तरह का एक प्रस्ताव रक्षा सेबाओं से आया था जिसमें उन्होंने उद्यान के सबसे ऊंचे स्थान पर एक निरीक्षण चौकी के निर्माण के लिए पांच किलोमीटर लंबी सड़क बनाने की इच्छा जाहिर की. गोरेगांव को पूर्व में ठाणे और पश्चिम में मलाड से जोड़ने और पार्क को दो हिस्सों में बांटते हुए एक सड़क बनाने का एक प्रस्ताव रखा गया था. समाजवादी नेता मृणाल गोरे और दूसरे नेताओं ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था लेकिन अदालत की निषेधाज्ञा के कारण यह प्रस्ताव रद्द हो गया.

बोरीवली उद्यान 250 तरह के पक्षियों और 42 किस्म के स्तनपायी जानवरों का घर है. वन्य जीवन पर लिखने वाले, फोटोग्राफर संजय मोंगा कहते हैं, "मुझे जब भी मौका मिलता है मैं जंगलों में जाता हूं. चारों ओर चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देती है. और जंगली घासपात की खुशबू महकती है..." इस अभयारण्य को सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहला कदम उद्यान में रह रहे 500 लोगों को दूसरी जगह बसाना है. आखिर तेंदुओं के हमले उद्यान को लपेट में लेने वाली समस्याओं के लक्षण हैं, उनके कारण नहीं.

—सलिल त्रिपाठी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लॉन टेनिस

घाटा ही घाटा

डेविस कप में इज़राएल से नहीं खेलेंगे

इस बार भारतीय डेविस कप टीम को 1 अप्रैल को तेल अवीव पहुंचने का जो आदेश मिला वह आखिरकार 'अप्रैल फूल' जैसा लतीफा ही सिद्ध हुआ. तारीख से एक हफ्ता पहले ही प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संसद में घोषणा की कि भारत ने इज़राएल के साथ डेविस कप मुकाबले में हिस्सा न लेने का फैसला किया है.

स्पष्ट है कि भारत ने यह फैसला अरब देशों की नाराजगी को देखते हुए किया है. लेकिन यह भी तय है कि इस फैसले ने भारतीय टेनिस के लिए नए संकट खड़े कर दिए हैं. इस फैसले की वजह से भारत को अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ (आईटीएफ) के नियमानुसार जुर्माना भरना होगा जो कम-से-कम दस हजार डॉलर से लेकर एक लाख डॉलर तक कुछ भी हो सकता है. इसके अलावा यदि महासंघ चाहे तो आगामी सिओल ओलंपिक में भारत के विजय और आनंद अमृतराज तथा रमेश कृष्णन को सीधे भाग लेने से रोक सकता है. पिछले साल डेविस कप फाइनल में पहुंचने के कारण भारत को मुकाबले में सीधे शामिल होने की छूट मिली थी.

भारतीय फैसले के कई दूर-गामी परिणाम भी हो सकते हैं. न खेलने के फैसले की वजह से भारत को डेविस कप मुकाबलों से तीन साल के लिए बाहर भी किया जा सकता है. पर यह इस पर निर्भर करता है कि भारत अपना पक्ष कैसे पेश करता है. भारत अपने प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य का हवाला अवश्य देगा कि "भारत इज़राएल के साथ पहले भी खेल चुका है और भविष्य में भी खेलना चाहेगा." और यह भी कि इज़राएल के अरब आबादी वाले क्षेत्रों में असंतोष को देखते हुए वह किसी तीसरे तटस्थ देश में खेलने को तैयार है. मगर इस बात की गारंटी नहीं कि महासंघ भारत की इन दलीलों को मान ही ले.

भारतीय दल के मैनेजर पी.एल. रेड्डी स्वीकार करते हैं कि "पिछले मामलों में भी स्थान बदले जाने के आग्रहों को महासंघ ने हमेशा ठुकराया ही है. नियमानुसार केवल किसी प्राकृतिक संकट में ही स्थान बदलने की अनुमति दी जाती है. इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि इज़राएल भारत के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करे."

भारत को निलंबित किए जाने का एक नतीजा यह होगा कि उसे एशिया-ओसिएनिया क्षेत्र के ग्रुप-2 में रख दिया जाएगा. इसका मतलब यह हुआ कि विश्व की पहली 16 टीमों में आने के लिए उसे नए सिरे से मलेशिया और सिंगापुर के साथ मुकाबले खेलने होंगे. इससे भारत के टेनिस प्रबंधकों के लिए नया सिरदर्द पैदा होना निश्चित है. ज़ीशान अली (18) और मार्क फरेरा (20) जैसे युवा खिलाड़ी भले ही अब डेविस कप के दरवाजे पर दस्तक देने की हालत में आ चुके हैं पर अंतरराष्ट्रीय मैचों के अनुभव के अभाव में उनका यह सफ़र सामान्य से ज्यादा लंबा हो जाएगा.

इस संकट में आ फंसने का एक कारण यह भी है कि भारत अमृतराज बंधुओं पर अपनी निर्भरता कम नहीं कर पाया है. हर मुकाबले में उन्हें उतारते रहने से युवा खिलाड़ियों की उपेक्षा होती रही है. इसके अलावा दूसरे खतरे भी हैं. एक खतरा तो यही है कि दो साल के निलंबन से युवा खिलाड़ी उस अंतरराष्ट्रीय अनुभव से वंचित हो जाएंगे जिसकी उन्हें अब बहुत ज्यादा जरूरत है.

शायद अभी से किसी बड़े परिवर्तन की उम्मीद करना बेमानी होगी. संभावित जुर्माने की बात करते हुए विजय कहते हैं, "हमारा मामला काफी मज़बूत है. सिओल मुकाबले सितंबर में होने के कारण ही इस मैच को अप्रैल के लिए रखा गया था. अब इसे अगर जुलाई में भी खेला जाए तो भी सिओल से पहले तीन महीने का समुचित समय होगा."

यदि विजय का यह आशावाद सच्चा साबित होता है और महासंघ भी भारत को कोई बड़ी सजा नहीं देता तथा इज़राएल के साथ किसी दूसरे स्थान पर मैच कराया जाता है तो इसका एक बड़ा नुकसान यह होने वाला है कि खेल पर विजय और आनंद का कब्ज़ा बना रहेगा और युवा खिलाड़ी लाइन में खड़े थकते रहेंगे. भारतीय टेनिस के लिए यह हालत यकीनन उस स्थिति के मुकाबले कहीं खराब होगी जब उसे खेल से निलंबित कर दिया जाए.

—बी. राम

प्रदीप मधानी

आनंद और विजय अमृतराज (ऊपर); जीशान (बाएं) और फरेरा: कठिन वक्त

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सिर्फ एक दवा खोज निकालने के लिए 8,000 सम्मिश्रणों की जांच-परख सार्थक रही!

इस बच्चे का जीवन बच गया.

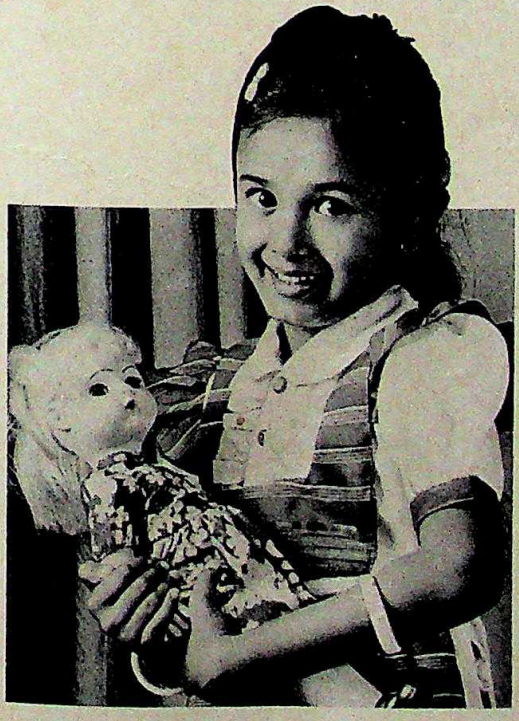

हॅक्स्ट को इस बच्चे की तरह, लाखों जीवनों की चिंता है. और बेहतर दवाओं की खोज चलती ही रहती है. कभी-कभी तो एक दवा खोज निकालने के लिए 8,000 सम्मिश्रणों को परखा जाता है. इसमें 10 साल तक भी लग जाते हैं. साथ ही साधनों की असीम लागत.

लेकिन भारत में कहीं-न-कहीं, किसी रोगी की जान बच जाती है. किसी बच्चे की भीषण मेनिन्‌जाइटिस् का इलाज हो सका. किसी परिवार की छूत की बीमारी से रक्षा होती है. यानी हॅक्स्ट दवा, इन में से हरएक जीवन को बचाकर, उसे बेहतर बनाकर, पूरे प्रयत्न को सार्थक बनाती है.

आज, हृदय और परजीवी-संक्रमण के इलाज के लिए जीवन-रक्षक दवाएं, अलर्क रोग से बचाव के टीके, और प्लाज्मा प्रतिकल्प, जो शॉक और सेफ़ालोस्पोरिन के लिए, हॅक्स्ट के कुछ ऐसे उत्पादन हैं, जो एक नया जीवन-दान देते हैं. और हॅक्स्ट रोग-निदान उपकरणों की मदद से जिगर-विकार और ऍक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल एमोबियासिस् जैसी बीमारियों का ज्यादा सही पता लगाया जा सकता है, जिससे हर कहीं लोगों का कल्याण हो.

हॅक्स्ट, मनुष्यों, पशुओं और पौधों का जीवन-स्तर ऊपर उठाने के लिए वचनबद्ध हैं. लगातार खोजबीन से औषध-रसायनों पशु-चिकित्सा के उत्पादनों और खेती रसायनों के विकास से जीवन को सुरक्षित और विकसित करने के लिए.

स्वास्थ्य की देखरेख के कार्यक्रमों, जैसे मधुमेह-पहचान के कैंपों के माध्यम से . चिकित्सा शिक्षा सेवाएं प्रदान कर के. और भारत में हर संभव दृष्टि से जीवन-स्तर ऊपर उठाकर.

हॅक्स्ट इण्डिया

औषध-रसायनों के निर्माता

क्योंकि जीवन मूल्यवान है.

Hoechst

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

ULKA-HI-3-88 HIN

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भवान सिंह

मादक दवा नियंत्रण

कामयाबी की नई उम्मीदें

भारत की मादक दवा विरोधी कोशिशों को मान्यता

दिल्ली पुलिस के लिए इससे बढ़िया अवसर नहीं हो सकता था. ठीक उसी वक्त जब दुनिया भर में मादक दवाओं के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के 40 से भी ज्यादा अगुआ राजधानी में उच्चस्तरीय सम्मेलन में व्यस्त थे, पुलिस ने दरियागंज के नरेश कक्कड़ को लगभग 12 करोड़ रुपए की हेरोइन के साथ धर दबोचा. बाद में की गई जांच-पड़ताल से 33 वर्षीय महिला पिंकी गुलजार भी पकड़ी गई. खबर है कि यह महिला कक्कड़ के साथ दुबई के एक माफिया सरगना भजन सिंह की अगुआई में मादक दवाओं की तस्करी के रैकेट में भी शामिल थी. यह भी पता लगा कि इन संदिग्ध अपराधियों के पंजाब में तस्करों के गिरोहों से भी गहरे रिश्ते हैं. गिरोह आतंकवादियों को हथियार मुहैया कराता था.

जब्त की गई हेरोइन सम्मेलन के सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के महत्व को उजागर करती है. यूरोप और भारतीय उपमहाद्वीप के मादक दवा नियंत्रण सेवाओं के मुखियाओं के इस अंतरक्षेत्रीय सम्मेलन में मुख्य मुद्दा यह था कि भारत अब हेरोइन की तस्करी का एक प्रमुख रास्ता बन गया है. इंटरपोल द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में पुलिस प्रधानों ने इस अपराध तथा मादक दवाओं की तस्करी और आतंकवाद के नापाक गठजोड़ के खिलाफ लड़ने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग जुटाने पर विचार किया.

दिल्ली पुलिस जहां इस सामयिक सफलता पर खुश थी, वहीं भारतीय प्रतिनिधिमंडल सम्मेलन में इस बात का जोर-शोर से खडन कर रहा था कि भारत नशीली दवाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अंतरराष्ट्रीय अभियान में पिछड़ गया है. प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि भारत तो इस मुहिम में सबसे ज्यादा कामयाब साबित हो रहा है. नवगठित संस्था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के महानिदेशक बी.वी. कुमार बताते हैं, "पिछले तीन वर्षों में यूरोप में जब्त की गई हेरोइन में भारत से जाने वाली हेरोइन की मात्रा आधी रह गई है. हम इसका पूरा श्रेय खुद नहीं लेना चाहते लेकिन हमने कोई कम कोशिश नहीं की है." (चार्ट देखें) इंटरपोल के महासचिव और इस सम्मेलन के अध्यक्ष रेमंड ई. केंडल ने भी भारत की सफलता को सराहा.

यूरोप की मादक दवा निरोधक एजेंसियां इंटरपोल से बार-बार शिकायत कर रही थीं कि उन्हें भारत से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा. पाकिस्तान की ओर से लगातार किए जा रहे इस प्रचार ने भी भारत की परेशानी बढ़ा दी थी कि भारत तस्करों को पकड़ने की उसकी कोशिशों में पूरा सहयोग नहीं कर रहा.

लेकिन जब सम्मेलन में रखे आंकड़ों ने इन आरोपों को झुठला दिया तो पाकिस्तान ने तुरंत पैंतरा बदल लिया. उसका दावा था कि भारत की इस कामयाबी का श्रेय भी पाकिस्तान को ही है क्योंकि पाकिस्तान नई दिल्ली को इस बारे में महत्वपूर्ण खुफिया जानकारियां देता रहा था. इस पर केंडल ने कहा, "जब अठारह महीने पहले सम्मेलन आयोजित किया गया था तब पश्चिम को जाने वाली हेरोइन का अधिकांश भाग भारत से ही

नई दिल्ली में इंटरपोल का सम्मेलनः बढ़िया तालमेल

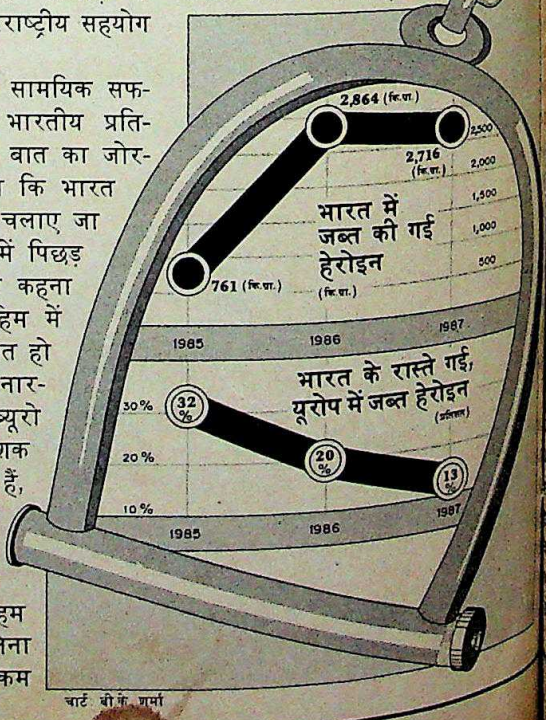

चार्ट बी.के. शर्मा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आंध्र प्रदेश

रक्तरंजित संघर्ष गाथा

विजयवाड़ा में नेताओं के गिरोहों की लड़ाई का नया मोर्चा

देवीनेनी मुरली नहीं जानता था कि एक हफ्ते से उसकी निगरानी की जा रही है. एक कुख्यात गिरोह का यह सरगना जब नेल्लोर से अपने गृहनगर विजयवाड़ा की ओर लौट रहा था तो उसे पता भी नहीं चल पाया कि एक कार उसकी वैन का पीछा कर रही है. कार तीन बार गाड़ी से आगे निकलकर फिर पीछे रह गई पर साथ बैठे गिरोह के दूसरे लोगों को भी शुबहा नहीं हुआ.

लेकिन जैसे ही मुरली की गाड़ी उजाड़-से इलाके में पहुंची, एक ट्रक ने सीधे वैन में टक्कर मार दी. इससे पहले कि उसमें बैठे

सभी फोटो: के. मूर्ति

मुरली (बीच में) के साथ अन्य मृतक

सात व्यक्ति कुछ कर पाते, ट्रक में से कूदे 20 हथियारबंद लोगों ने उन्हें घेर लिया. मुरली और उसके चार साथियों की छुरा मारकर हत्या कर दी गई. उसके दो साथी ही भागने में कामयाब हो पाए. कुछ ही मिनटों बाद हत्यारे आराम से ट्रक में बैठकर भाग गए.

10 मार्च को हुई ये हत्याएं दो स्थानीय गिरोहों के बीच बदले की कार्रवाइयों की ताजा कड़ी हैं. इससे कृष्णा नदी के तट पर बसा व्यवसायी नगर विजयवाड़ा धधक उठा. मुरली के भाई देवीनेनी नेहरू शहर से सटे कांकीपाडु हलके से तेलुगु देशम के विधायक हैं. इससे स्थिति और भी गंभीर हो उठी. मुरली और नेहरू के समर्थकों ने तुरंत ही विजयवाड़ा में ऊधम मचाकर दुकानें बंद करवा दीं. अगले दिन फिर बंद रखा गया. शहर भर में डर फैल गया. लारियों में भरकर जब शवयात्रा शुरू हुई तो क्रुद्ध शवयात्रियों ने शहर इंका के दफ्तर पर हमला बोल दिया.

नेहरू का आरोप है कि इन हत्याओं की योजना विजयवाड़ा के इंका विधायक वंगवीती मोहन रंगाराव ने बनाई थी. ज्यादातर रंगा नाम से जाने-माने इस विधायक के फोटो अनेक स्थानीय पुलिस थानों में कुख्यात अपराधियों के साथ लगे हुए हैं. पर उस समय रंगा सांस की तकलीफ के कारण दिल्ली के राममनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती थे.

मृतकों के समर्थकों को संदेह था कि रंगा षड्यंत्र के तहत जानबूझकर मौका-ए-वारदात से दूर रहे थे. मृतकों के समर्थकों ने एक कम्युनिस्ट अखबार के पूर्व संपादक और अब इंका कार्यकर्ता कटरगड्डा राजगोपाल राव के घर को निशाना बनाया और पथराव किया.

दुर्भाग्य से जब गड़बड़ी शुरू हुई उस समय विजयवाड़ा और दूसरी जगहों की पुलिस राज्यव्यापी ग्राम पंचायत चुनावों में लगी हुई थी. इसलिए जब मुरली और नेहरू के समर्थकों ने शहर के गली-कूचों में आतंक फैला दिया तो स्थानीय पुलिस भौंचक रह गई. राज्य की गिनी-चुनी महिला आईपीएस अफसरों में से एक, विजयवाड़ा की पुलिस अधीक्षक अरुणा बहुगुणा मानती हैं, "शुरू में हमें असुविधा जरूर हुई क्योंकि तकरीबन सभी पुलिस वाले चुनाव ड्यूटी पर थे. लेकिन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शवयात्रा के लिए हमें वक्त पर ही अतिरिक्त जवान मिल गए."

पर इतना स्पष्ट है कि पुलिस के पास इतने जवान नहीं थे कि वह दंगा होने से पहले विजयवाड़ा के जाने-माने गुंडों को हिरासत में ले पाती. नेहरू इस बात का खंडन करते हैं कि गड़बड़ी तेलुगु देशम या उनके भाई के समर्थकों ने फैलाई. वे कहते हैं, "जब मैंने पथराव करते कुछ नौजवानों का परिचय पूछा तो उन्होंने खुद को मेरा समर्थक बताया, हालांकि मैं उन्हें जानता तक न था." मगर पुलिस के जांचकर्ता

वी.एम. रंगाराव

इंका विधायक रंगा और तेलुगु देशम विधायक नेहरू के गिरोहों के झगड़े में अनेक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है

देवीनेनी नेहरू

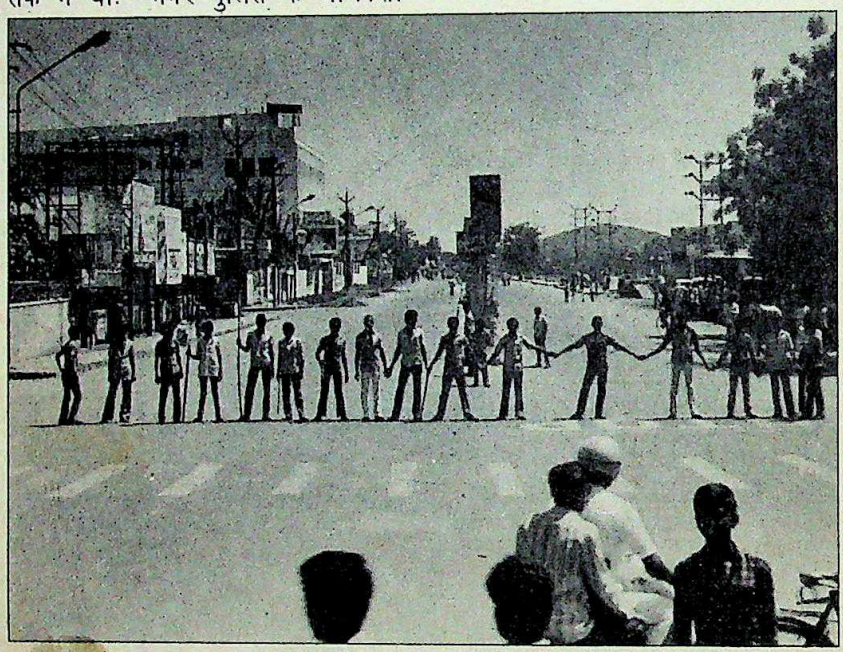

बंद कराते नेहरू के समर्थक

बताते हैं कि दंगई नेहरू की यूनाइटेड स्टुडेंट्स आर्गेनाइजेशन (यूएसओ) के लोग थे.

दरअसल दोनों विधायकों के बीच काफी लंबे अर्से से चले आ रहे इसी विवाद की वजह से न सिर्फ बहुत-सी हत्याएं हुई हैं बल्कि यूएसओ भी वजूद में आई. 1973 में यूनाइटेड इंडिपेंडेंट्स नामक एक युवा क्लब ने भारी मात्रा में चंदा इकट्ठा किया था. नेहरू और उनके बड़े भाई देवीनेनी गांधी ही रंगा और उनके बड़े भाई वंगवीती राधाकृष्णमूर्ति (जिन्हें राधा के नाम से जाना जाता था) की ओर से क्लब का कामकाज देखा करते थे. बाद में इस भारी रकम की हिस्सेदारी पर झगड़ा हो गया.

1974 में राधा की हत्या से हिंसा का जो सिलसिला शुरू हुआ पिछले महीने की घटना उसकी ताजा मिसाल है. इस हत्या के बाद जब रंगा ने आगे आकर संगठन का पैसा राधा मित्रमंडली नाम की एक संस्था को देना शुरू किया तो गांधी और नेहरू ने उनके नेतृत्व को चुनौती दी. मित्रमंडली में जातिगत आधार पर फूट पड़ गई. कापू जाति के लोग रंगा के साथ रहे जबकि कम्मा गांधी और नेहरू के साथ चले गए.

सन 1979 में फिर हिंसा हुई. आरोप लगा कि रंगा और उसके साथियों ने विजयवाड़ा के आंध्र लोयला कॉलेज के परिसर में गांधी की हत्या कर दी थी. बदले में एक साल बाद नेहरू, उनके भाई मुरली और दूसरे लोगों पर आरोप लगा कि उन्होंने एक बस से रंगा के समर्थकों को घसीटकर एक की हत्या कर दी. साथ में एक निर्दोष बसयात्री भी मारा गया था.

मगर हत्या के ये दोनों मामले जब कड़ी सजा देने के लिए मशहूर एक मजिस्ट्रेट के सामने सुनवाई के लिए आए तो बताया जाता है कि रंगा और नेहरू ने समझौता कर लिया. दोनों ओर के गवाह मुकर जाने से मुकदमे खत्म हो गए और सभी लोग बाइज्जत बरी कर दिए गए.

इसका यह मतलब नहीं कि विजयवाड़ा में शांति हो गई थी. 1983 में नेहरू तेलुगु देशम के टिकट पर विधायक हो गए और 1985 में वे फिर जीते. उनकी पूछ बढ़ गई. इस बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए रंगा इंका के सक्रिय कार्यकर्ता बन गए.

जून 1983 में जब सरकार ने विजयवाड़ा को एक अलग शहरी पुलिस जिला बनाने और बड़े शहरों की तरह वहां आयुक्त प्रणाली लागू करने का फैसला किया तो रंगा की अगुआई में इंका ने इसका विरोध किया. योजना सिरे न चढ़ सकी. उसी साल मुख्यमंत्री नंदमूरि तारक रामराव ने दोनों गिरोहों की गतिविधियों को रोकने के लिए एक सख्त पुलिस अफसर के.एस. व्यास को बतौर पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया. व्यास ने हालांकि शहर में कुछ हद तक व्यवस्था बहाल कर दी पर रंगा ने भी पुलिस की सख्ती का फायदा उठाया. वे 'पुलिस जुल्म' के विरोध में बार-बार भूख हड़ताल करके लोगों की सहानुभूति पाने में कामयाब रहे. इससे उन्हें इंका का टिकट पाने और नेहरू के साथ ही विधानसभा में पहुंचने में मदद मिली.

पुलिस के जांचकर्ताओं का मानना है कि हाल की हत्याएं पिछले मई में रंगा के प्रमुख साथी मुत्यालु सौभांद्री की हत्या के बदले की गई हो सकती है. दोनों गुटों के महत्वपूर्ण व्यक्ति हालांकि खत्म कर दिए गए हैं पर विजयवाड़ा के लोगों को विश्वास नहीं कि यह रक्तरंजित कहानी खत्म हो गई है.

ताजा मामले में जिन 13 लोगों के नाम वारंट जारी किए गए हैं उनमें रंगा नहीं हैं. पर इंका विधायक ने अग्रिम जमानत करा ली है. वे 21 मार्च से चल रहे विधानसभा सत्र में भी तुरंत नहीं पहुंचे. दोनों विधायकों की पीठ पर उनकी अपनी-अपनी पार्टी की ताकत होने से आश्चर्य नहीं कि यह विवाद आने वाले वर्षों में भयानक मोड़ ले ले.

—अमरनाथ के. मेनन, विजयवाड़ा से

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

फोटो: विमल गुप्ता

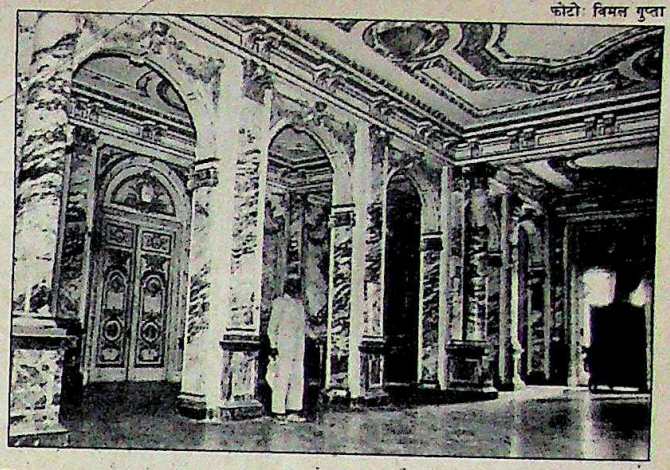

इंदौर महल का अग्रभाग ढहने की स्थिति में (बाएं); और अलंकृत अंदरूनी भाग

विरासत का विनाश

लालबाग रजवाड़े की हालत खस्ता

इंदौर के लालबाग रजवाड़े के एक कमरे में लगी लकड़ी की अलमारी हालांकि अब बिलकुल खाली है लेकिन एक जमाने में इसमें रखे कीमती इत्रों की खुशबू आज भी इससे आती है. 1978 में अपनी मौत तक इसी महल में रहे तुकोजी राव होल्कर इन कीमती इत्रों के खासे शौकीन थे.

कभी होल्कर राजाओं का प्रासाद रहा और मध्य भारत के सबसे खूबसूरत उद्यान महलों के लिए विख्यात रहा लालबाग रजवाड़ा आज विनाश के कगार पर खड़ा हुआ है. चार एकड़ में फैला यह तिमंजिला महल आज मरम्मत का मोहताज है. दीवारों का पलस्तर उतर चला है, इटालियन शैली पर निर्मित छत्रों में दरारें पड़ गई हैं, छतें चूने लगी हैं, और तो और महल में लगा 75,000 वर्ग फीट संगमरमर भी देखभाल के बिना बरबाद हो रहा है.

मध्य प्रदेश के पुरातत्व विभाग को 1982 में ही पता लग गया था कि दीवारों की सुनहरी सज्जा को खुरच डाला गया है. महल के भीतरी भाग में फांस के वरसैलिज शैली पर हुई सज्जा को भी भारी नुकसान पहुंचा है. तुकोजीराव की अमेरिकन विधवा महारानी देवी शिकायती लहजे में कहती हैं, 'मुझे तो कहीं किसी किस्म का रख-रखाव नजर नहीं आता.'

इटली के संगमरमर, फ्रांस की चेदन की लकड़ी और यहीं के जयपुरमर के टुकड़ों से निर्मित, 45 कमरों वाले इस रजवाड़े का 20 एकड़ में फैला बगीचा और उसमें लगे फव्वारे कभी विशिष्ट आकर्षण पैदा करते थे. महल की दीवारों और छतों पर खूबसूरत तस्वीरें लगी हुई हैं. बताया जाता है कि ये तस्वीरें पचास साल पहले रूसी चित्रकार रोरिक ने बनाई थीं. होल्कर परिवार का उषा ट्रस्ट जिसका, हाल तक इस रजवाड़े पर नियंत्रण था, ने पूरे फर्नीचर, पुरानी कलाकृतियों और दूसरे सामान की कीमत 25 लाख रुपए आंकी है.

लेकिन बड़ी संख्या में कलाकृतियों के 'गायब होने' की खबर चौंका देने वाली है. ये कहां गईं, किसी को पता नहीं. जबकि उषा ट्रस्ट का दावा है कि इसे जो कुछ तुकोजीराव से मिला था, लालबाग में ज्यों का त्यों रखा है. लेकिन पुरातत्व विभाग का कहना है कि बड़े सुनियोजित ढंग से इन कलाकृतियों की चोरी होती रही है.

चोरी की गई दुर्लभ किताबों में 'लेडी आफ लोटस' भी है, जिसमें मालवा की कुछ अद्भुत कलाकृतियां भी लगी हुई थीं. इनमें एक अलंकृत मेज भी है जिसमें चार पायों की जगह चार खूबसूरत मूर्तियां लगी हुई थीं. अब इसका एक पाया गायब है. इसके गुम हो जाने से मेज की कीमत सिर्फ पांच हजार रुपए रह गई है.

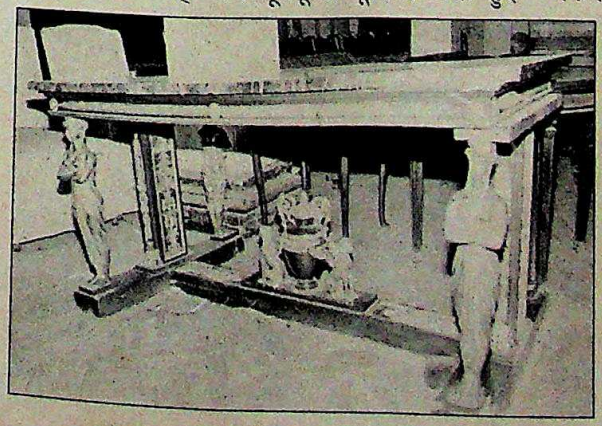

अलंकृत मेज जिसका एक पाया गायब है

हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले साल रजवाड़े का अधिग्रहण कर लिया था, पर उसने रजवाड़े की खस्ता हालत सुधारने के लिए कुछ खास नहीं किया है. इतने विशाल परिसर की देखभाल के लिए केवल चार होमगार्ड तैनात किए गए हैं. रजवाड़े के फर्नीचर, किताबों, गलीचों और पुरातन कलाकृतियों की देखभाल के लिए उषा ट्रस्ट ने 17 कर्मचारी नियुक्त किए हैं. अभी तक ये चीजें सरकार ने अपने कब्जे में नहीं ली हैं.

राज्य सरकार ने लालबाग पैलेस और उसके चारों ओर की 72 एकड़ जमीन 64.46 लाख रुपए में अधिग्रहित की थी. इंदौर के जिलाधीश ओ.पी. रावत कहते हैं, "मुझे बताया गया है कि आज सिर्फ जमीन की कीमत ही 2.5 करोड़ रुपए होगी." फिर भी सरकार रजवाड़े के फर्नीचर और कलाकृतियों को अपने कब्जे में लेने से हिचकिचा रही है. यह हिचकिचाहट पैसे को लेकर है. उषा ट्रस्ट इस सबकी कीमत 25 लाख रुपए मांग रहा है जबकि सरकार 9 लाख रुपए दे रही है.

होलकर परिवार ने एक बार इस ऐतिहासिक धरोहर-रजवाड़े को एक निजी संस्था को बहुमंजिला शॉपिंग कांप्लेक्स बनाने के लिए बेचने का प्रयास किया था. लेकिन लोगों के विरोध के कारण राज्य सरकार को इसे खरीदकर शहर की जनता को समर्पित करने के लिए मजबूर होने पड़ा था.

—नरेंद्र कुमार सिंह इंदौर में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

टीपू सुल्तान के वंशज

जाने कहां गए वो दिन

वैभवशाली शाही खानदान के तंगहाल वंशज फाकाकशी को मजबूर

एक रिक्शा चलाता है, दूसरे ने मिट्टी के तेल की डीलरशिप ले रखी है तो तीसरा कपड़ों की तिजारत करता है. ये लोग तो फिर भी किस्मत वाले हैं. खानदान की दूसरी शाखा के लोग कलकत्ता के टॉलीगंज में रेड लाइट एरिया से सटी और बदबूदार नालियों से घिरी एक जर्जर दोमंजिली इमारत में किसी तरह दिन गुजार रहे हैं. गरीबी इस कदर है कि चूल्हा जलाने के लिए खानदान के लोगों ने हवेली के खिड़की-दरवाजे उखाड़-उखाड़कर ईंधन के बतौर इस्तेमाल कर लिए.

फटेहाली और कंगाली का आलम देखिए कि हवेली में रहने वालों और आसपास बसे लोगों में कोई अंतर ही दिखाई नही देता पर हवेली के बाशिंदे औरों से अलग हैं. वे मैसूर राजघराने के सबसे मशहूर बेटे फतेह अली शाह टीपू सुल्तान के वंशज हैं. इतिहासकार टीपू सुल्तान को 'मैसूर का शेर' कहते हैं. अपनी रणनीतिक कुशलता और राजनैतिक सूझबूझ के कारण विख्यात हुआ यह देशभक्त सुल्तान मई 1799 में श्रीरंगपत्तनम में अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गया था.

आज इस गौरवशाली वंश के सामने जीवन-मरण का सवाल आ खड़ा हुआ है. इससे भी बड़ी बात यह है कि देश के सबसे बड़े और धनवान मुस्लिम ट्रस्ट, प्रिंस गुलाम मुहम्मद ट्रस्ट का उत्तराधिकारी होने के बावजूद उनकी यह हालत है. यह ट्रस्ट कलकत्ता के टॉलीगंज क्लब और रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब जैसी शहर की कई कीमती जायदादों का मालिक है.

बढ़-चढ़कर किए गए दावों के कारण टीपू सुल्तान के वंशजों को गुलाम मुहम्मद ट्रस्ट से नाममात्र मदद ही मिल पाई

टीपू सुल्तान के 12 बेटे थे जिन्हें अंग्रेजों ने कलकत्ता लाकर टॉलीगंज में रहने के लिए जगह दे दी थी. तब यहां जंगल हुआ करता था. इनमें से सात बेटों का कोई मर्द वारिस नहीं हुआ. बाकी पांच में से सिर्फ दो भाइयों, मुनीरुद्दीन और गुलाम मुहम्मद के वारिसों का ही पता चलता है.

मुनीरुद्दीन के वंशज तो छोटे-मोटे धंधे करके गुजर कर रहे हैं पर गुलाम मुहम्मद के वंशज टॉलीगंज की इस ढहती हवेली मे फाका-कशी के दिन गुजार रहे हैं. एक और दूर के वंशज मकबूल आलम, प्रिंस अनवर शाह रोड पर लाल ईंटों के एक घर में किसी तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं. इमारत की पहली मंजिल के हॉल को किराए पर उठा दिया गया है. लकड़ी की सीढ़ी के नीचे की और साथ लगी खुली जगह मोटर मेकनिकों को दे दी गई है. मकबूल आलम कहते हैं, "आखिर हमें जिंदा तो रहना है. हमारे पास पुरखों की बहुत संपत्ति नहीं और न ही गुलाम मुहम्मद ट्रस्ट से हमारा किसी किस्म का लेना-देना है."

उधर मुनीरुद्दीन के वंशज मुहम्मद हुसैन शाह कलकत्ता के लोअर सर्कुलर रोड पर ऐसे ही एक खस्ताहाल बंगले में अपने चार भाइयों और मां के साथ रहते हैं.

टीपू सुल्तान

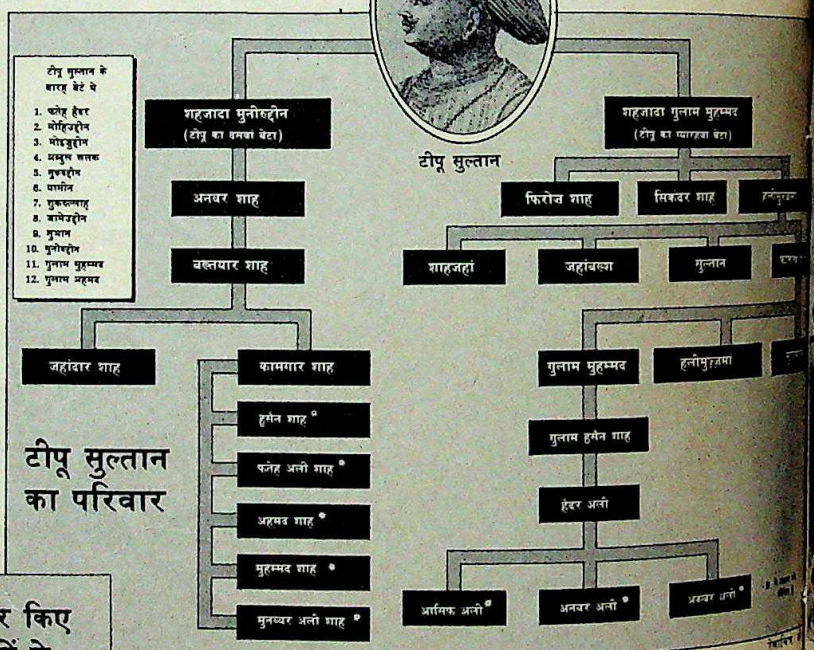

टीपू सुल्तान का परिवार

सभी फोटो: कल्याण चक्रवर्ती

अनवर अली: कभी राजकुमार थे, आज रिक्शा चलाने पर मजबूर हैं

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

...ीन के वंशजों ने बिहार के 1000 वर्ग ...ीटर क्षेत्र में फैली धालभूमि खानों ...ई का अधिकार खरीदा था. लेकिन ...में बिहार सरकार ने यह अधिकार ...वापस ले लिया.

...के बाद से ये लोग छोटे-मोटे काम ...किसी तरह जीवन चला रहे हैं. 48 ...'राजकुमार' मुहम्मद हुसैन शाह ने ...तेल की डीलरशिप पाने में सफलता ...बाद में उन्होंने अपनी इसी खस्ताहाल ...के सामने एक मोटर गैराज शुरू ...उनका छोटा भाई कपड़े की दुकान ...है. मुहम्मद हुसैन शाह कहते हैं, ...वाजिब बकाए का मुआवजा पाने के लिए दफ्तरों और अदालतों के चक्कर लगाकर मैंने सेहत खराब कर ली. लेकिन मुझे लड़ाई बंद कर देनी पड़ी क्योंकि मुकदमे में सिर्फ पैसा ही नहीं, वक्त भी जाया होता है."

मुकदमों और एक-दूसरे से बढ़कर दावे करने के चक्कर में टीपू सुल्तान के वंशजों को गुलाम मुहम्मद द्वारा 1872 में बनाए गए ट्रस्ट से बहुत थोड़ी मदद ही मिल पाई या ज़रा भी मदद नहीं मिली. इस ट्रस्ट की संपत्तियों में टॉलीगंज क्लब, टीपू सुल्तान मस्जिद, रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब, टॉलीगंज रेसकोर्स, शॉ वैलेस बिल्डिंग, शाही मस्जिद, कई कब्रगाह और दक्षिण में टॉलीगंज से लेकर व्यावसायिक इलाके धर्मतल्ला तक में छोटे-मोटे कई प्लॉट शामिल हैं.

गुलाम मुहम्मद की मौत के बाद इस शाही परिवार के सदस्यों में खुद को असली वारिस साबित करने की होड़ मच गई. मामला 1944 में जाकर ही सुलट पाया. तब कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अमीर अली ने ट्रस्ट का कामकाज देखने के लिए पांच लोगों की समिति बना दी. राजकुमार गुलाम मुहम्मद के पांचवें वंशज राजकुमार हैदर अली को ट्रस्ट का पहला मुतवल्ली बनाया गया. हुसैन शाह कहते हैं, "अगर जायदादों की कीमत लगाई जाए तो यह ट्रस्ट सबसे अमीर है. लेकिन कुप्रबंध और भ्रष्टाचार इतना है कि इससे होने वाली आमदनी हमेशा खर्चों से कम ही रहती है."

ट्रस्ट का कामकाज चलाने के लिए समिति बन जाने के साथ ही इस परिवार के लोगों का महत्व कम हो गया और मुतवल्ली सिर्फ नाम का ही प्रमुख रह गया. ट्रस्ट के वित्तीय लेन-देन पर उसका कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं रह गया. नियंत्रण हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त ट्रस्टियों के हाथ में चला गया जो ट्रस्ट का रोज-ब-रोज का काम देखते हैं. समिति के सदस्यों में विवाद होने पर अदालत बीच-बचाव करती रही है और फैसले भी वही करती है. मुतवल्ली के अलावा बाकी सभी ट्रस्टी सहयोगी सदस्य जैसे रह गए हैं.

हैदर अली की मौत के बाद उनके सबसे बड़े बेटे 'राजकुमार' आसिफ़ अली को नया मुतवल्ली बनाया गया. आसिफ़ अली अपने ननिहाल, लखनऊ में ही पले-बड़े हुए थे और कभी-कभार ही पिता के पास कलकत्ता आते थे. पति से अनबन के कारण उनकी मां मायके में ही रहती थीं. वे हैदर अली के तौर-तरीकों और गैर-जिम्मेदाराना रवैये से खुश नहीं थीं. आसिफ़ अली को जानने वाले बताते हैं कि ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने बिक्री का काम शुरू किया था. पर मुतवल्ली बनने के बाद ट्रस्ट की आमदनी बढ़ाने पर पूरा ध्यान देने के लिए वह काम छोड़ दिया और लखनऊ से कलकत्ता चले आए.

पर जल्दी ही आसिफ़ अली इस नई जिम्मेवारी से जी चुराने लगे. वे लखनऊ लौट गए और अब कलकत्ता सिर्फ मासिक भत्ता लेने भर के लिए ही आते हैं. 1986 में

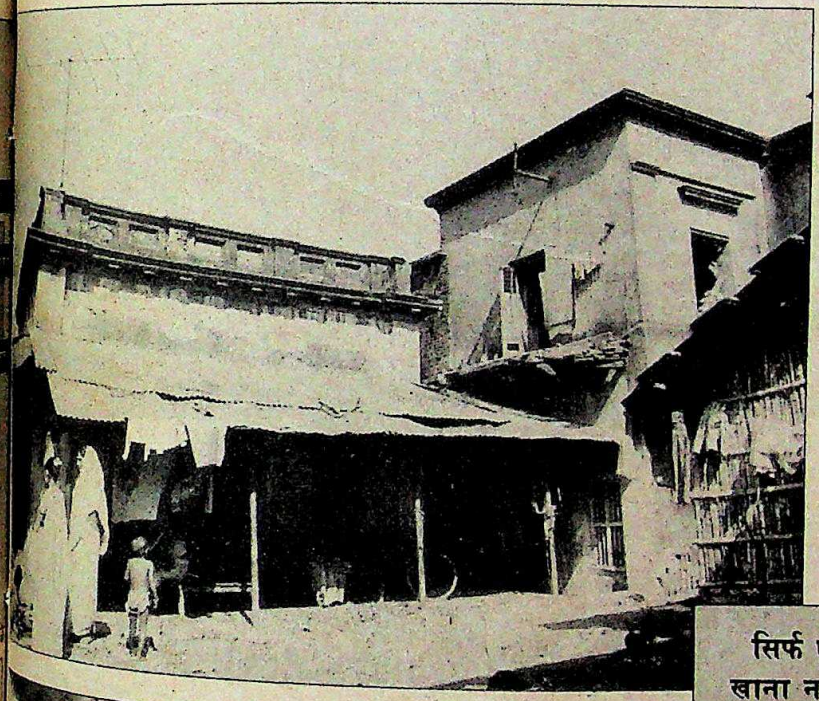

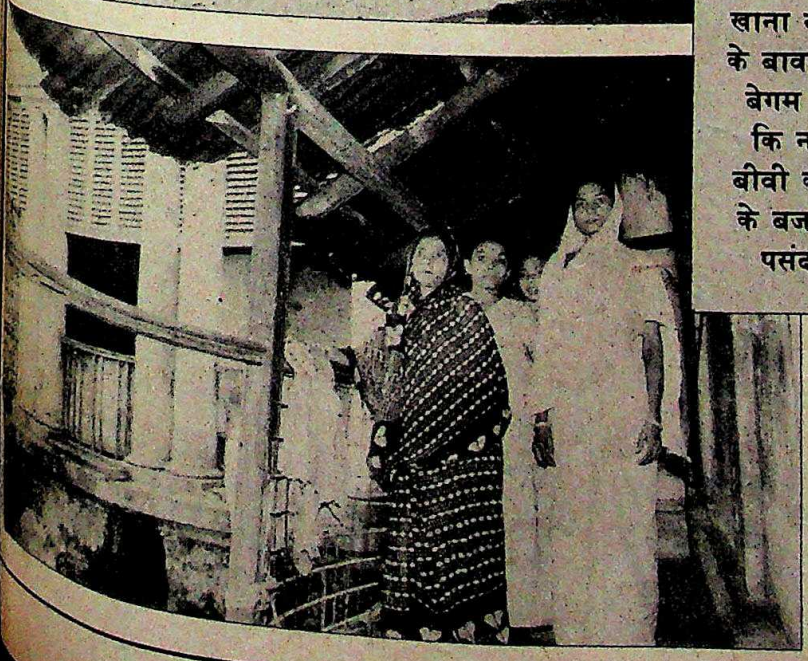

सिर्फ एक जून खाना नसीब होने के बावजूद हमीदा बेगम कहती हैं कि नवाब की बीवी काम करने के बजाय मरना पसंद करेगी

खस्ताहाल हवेली (ऊपर); और (नीचे) अपनी बेटियों के साथ हमीदा और जाहिदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हाईकोर्ट के आदेश से उनका भत्ता बढ़ाकर 1800 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है. आसिफ़ अली के न रहने से न सिर्फ ट्रस्ट के कामकाज पर ट्रस्टी मुहम्मद मोबिनुद्दीन का असर बढ़ गया है बल्कि आसिफ़ की दो सौतेली मांएं तथा पांच बच्चों की माली हालत भी बेहद खराब है.

बदबू बिखेरते 'टॉली नाले' से लगी हवेली में हैदर अली की दो बेवाएं बसर करती हैं. गुजर कैसे चलती है, यह पूछने पर हमीदा बेगम फूट पड़ती हैं, "नवाब साहिब ने हम लोगों के नाम बैंक में जो रकम जमा कर रखी है उससे हमें हर महीने ब्याज के 250 से 300 रुपए मिल जाते हैं. इसके अलावा हमें मकान का कुछ किराया भी मिल जाता है." जाहिदा बेगम कहती हैं कि रोजी कमाना उन्हें अच्छा नहीं लगता. वे कहती हैं, "हम कौन-सा काम कर सकती हैं? अगर हम काम करने लगें तो हमारे खाविंद की इज्जत को बट्टा लग जाएगा." हमीदा जोड़ती हैं, "हम अपनी बेटियों का निकाह कैसे करेंगी? नवाब हैदर अली की बीवी कहीं काम करने के बजाय मर जाना पसंद करेगी."

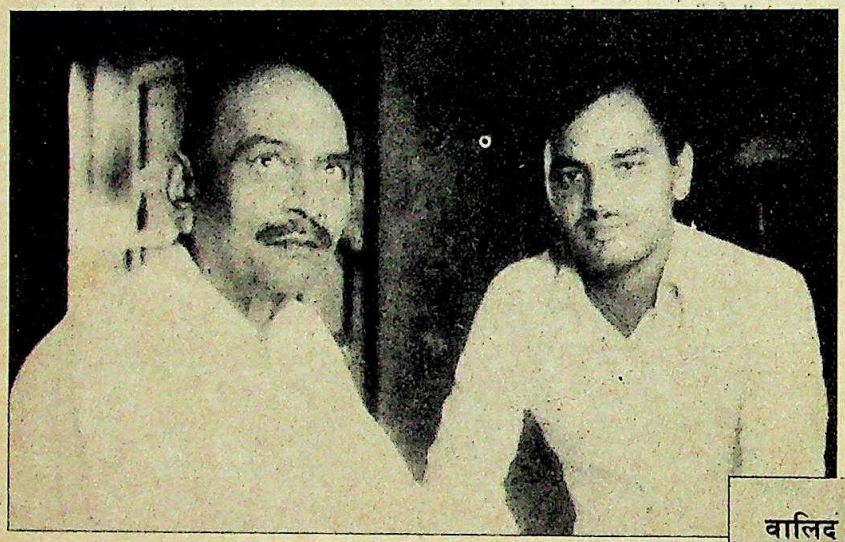

हैदर अली अपने बेटे आसिफ के साथ

पर बेगमों को अपने बच्चों की फिक्र है. वे कहती हैं, "नवाब की बेटियां किसी ऐरे-गैरे से नहीं ब्याही जा सकतीं." बेगमों को अच्छी तरह पता है कि आधा शहर तो 'हमारा' ही है. लेकिन हमीदा बेगम कबूल करती हैं कि कभी-कभी उन्हें एक जून का खाना ही नसीब हो पाता है.

हमीदा बेगम के सबसे बड़े लड़के, राजकुमार अनवर अली ने कहा कि वह और उनकी बहनें अब शाहनगर नगर-पालिका स्कूल में नहीं जातीं. उसने कहा, "फीस देने के लिए अब हमारे पास एक रुपया भी नहीं है. पढ़ाई बंद करने के बाद मैं मदद मांगने मोबिनुद्दीन के घर जाता रहा. दो बार उनके लोगों ने मुझे पीटा और एक बार पुलिस के हवाले कर दिया. उसके बाद मैंने वहां जाना बंद कर दिया." दोनों बेगमों का मानना था कि उनकी व उनके बच्चों की देखरेख का जिम्मा ट्रस्ट पर ही है.

मोबिनुद्दीन बेगमों के दावे को गलत बताते हैं. उनका कहना है कि राजकुमार गुलाम मुहम्मद के वक्फनामे (दानपत्र) में ट्रस्ट की गतिविधियां स्पष्ट रूप से परिभाषित की गई हैं. उसके मुताबिक ट्रस्ट का काम है—ईद के मौके पर कपड़े बांटना, रमजान के महीने में आम लोगों को खाना खिलाना, मुहर्रम में धार्मिक समारोह करना और अस्पताल तथा मदरसों को दान देना. वक्फनामे और बाद के अदालती आदेशों में कहा गया है कि शाही खानदान से बनाए गए मुतवल्ली को ही भत्ता दिया जाएगा. मोबिनुद्दीन स्पष्ट करते हैं, "हैदर अली की मौत के बाद से उनके सबसे बड़े बेटे आसिफ़ अली को यह रकम मिल रही है. अगस्त 1986 से यह रकम 1200 की जगह 1800 रुपए प्रतिमाह की जा चुकी है. अब इन औरतों और बच्चों की देखरेख का जिम्मा आसिफ़ अली का है, न कि ट्रस्ट का." वे सवाल करते हैं, "आप उनसे मिले हैं? क्या आप पक्के तौर पर मानते हैं कि वे शाही खानदान के हैं?"

इसके बाद भी, ट्रस्ट बस किसी तरह चल रहा है. जायदाद के अनुपात में ट्रस्ट की आमदनी बहुत कम होने की बात कबूल करते हुए मोबिनुद्दीन कहते हैं, "मैं क्या कर सकता हूं? ट्रस्ट की सारी जायदाद काफी पहले, 1947 से भी पहले, पट्टे पर उठाई जा चुकी है. 1986 तक ट्रस्ट की सालाना आमदनी सिर्फ 86,000 रुपए थी. यह रकम खास तौर पर किराए से आती थी. 1986 में शॉ वैलेस के नए प्रबंधकों ने किराया 2250 रुपए से बढ़ाकर 32,000 रुपए महीना करना मान लिया. तब से ट्रस्ट की सालाना आमदनी 3.75 लाख रुपए हो गई. अब हम अपनी धार्मिक और सामाजिक गतिविधियां बढ़ाएंगे."

एक ओर शॉ वैलेस ने किराया बढ़ा दिया पर 70 एकड़ जमीन पर कब्जा किए बैठे गोल्फ क्लब ने 'मुकदमे वगैरह' के कारण किराया चुकाना ही बंद कर दिया है. टॉलीगंज क्लब के कब्जे में 60 एकड़ जमीन है पर वह सिर्फ 600 रुपए महीना किराया ही अदा करता है. इसके बावजूद मुहम्मद मोबिनुद्दीन अपना भत्ता बढ़ाते रहे. अगस्त 1986 से उनका मासिक भत्ता 500 रुपए से बढ़कर 2000 रुपए हो गया है.

बेगमों का इलजाम है कि ट्रस्टी उन्हें 'हवेली के बाहर फेंकने' की साजिश रच रहे हैं. दोनों बेगमों का कहना है कि ट्रस्टी भ्रष्ट है और उसने ट्रस्ट की संपत्ति में अपनी जेबें भरी हैं. इन आरोपों पर मोबनुद्दीन का जवाब था, "ट्रस्ट का कामकाज अदालत से बहाल समिति देखती है. मैं तो ट्रस्ट का कर्मचारी भर हूं और सभी फैसलों पर समिति के लोगों की मंजूरी जरूरी होती है. शाही खानदान से मेरा कोई रिश्ता नहीं और न ही मुझे उसकी परवाह है."

वालिद की मौत के बाद आसिफ अली ट्रस्ट के मुतवल्ली बने. लेकिन वे जिम्मेवारी से जल्दी ही जी चुराने लगे

बावजूद इसके, यह हकीकत है कि टीपू सुल्तान का छठा वंशज 'राजकुमार' अनवर अली रिक्शा चला रहा है. अपने परिवार के सबसे बड़े पुरुष सदस्य, इस नौजवान राजकुमार को अपनी जिम्मेवारियों का एहसास है. वह कहता है, "मैं कुछ पैसे बचाना चाहता हूं. इन पैसों से मैं खुद का रिक्शा खरीदूंगा और ज्यादा पैसे कमाकर बहनों का निकाह करूंगा." गंदी, फटी लुंगी और टी-शर्ट पहने अनवर अली को भविष्य के बारे में कोई गलतफहमी नहीं है. "हो सकता कि मेरे छोटे भाई अकबर अली को भी रिक्शा चलाना पड़े." भारत के एक नामी शाही खानदान की यह कैसी दुर्दशा है!

—कमलजीत रतन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सिन्टेक्स - वक्त की कसौटी पर अव्वल, एकमात्र विश्वसनीय रेडीमेड पानी की टंकिया

सिन्टेक्स ने एक दशक से भी ज्यादा समय से सभी तरह की आबोहवाओ का सामना करके अपनी गुणवत्ता को साबित कर दिखलाया है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कोहिमा तक, पानी के संग्रह एवं परिवहन के सभी उपयोगोमें चल रही, लाखो सिन्टेक्स की टंकिया, अब दिन ब दिन और भी लोकप्रिय होती जा रही है !

कम्प्यूटर की सहायता से चलने वाले आधुनिक मशीनो पर अनोखे मोल्डींग प्रोसेस से बनी –सिन्टेक्स पानी की टंकियो के लाभ भी अद्वितीय है।

* वजन में हल्की * लगाने में आसान * मजबूत एवं टिकाऊ * देखभाल से मुक्त * १०० % लीकपूफ एवं रस्टपूफ * बहुत ही आरोग्यप्रद * १०० लिटर से २०,००० लिटर की विविध साईजो एवं आकारो में उपलब्ध * बिक्री उपरांत सेवा भारत में सर्वत्र.

अधिक जानकारी के लिये संपर्क करें :

सिन्टर प्लास्ट कंटेनर्स

प्लास्टिक्स डिव्हीजन : **दि भारत विजय मिल्स लि.** कलोल (उ. गुजरात) ३८२ ७२१ (भारत) दूरध्वनी: (०२७६४) २२२८, २२७४ २३५२, ३१४४, ३१४५. तार : 'SINTEX', टेलेक्स :०१२१/७२९६ BVM IN.

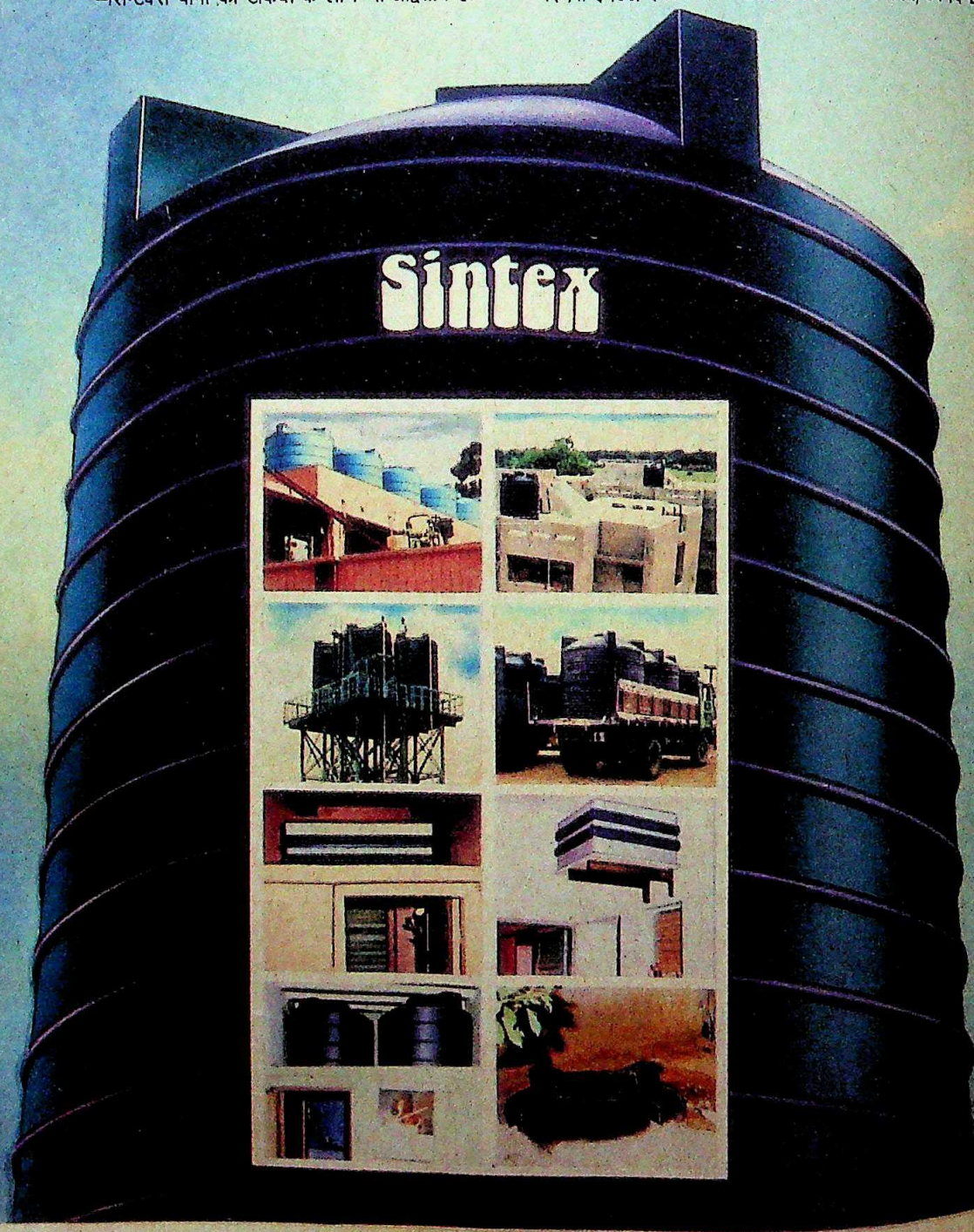

सिन्टेक्स - दुनियाकी नं.१ प्लास्टिक पानी की टंकि

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वेरका

देसी घी

100%

शुद्ध

वेरका देसी घी। स्वाद, शुद्धता व उत्तमता में लाजवाब। वेरका के बिना आपका भोजन अधूरा है।

मिल्कफ़ेड का एक उत्तम उत्पादन

MILKFED

द्वी पंजाब स्टेट कोआपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्ज़ फ़ेडरेशन लिमिटेड, एस० सी० ओ० न० 3015-16 सैक्टर 22-डी, चण्डीगढ़ - 160 022

UNION-2288

OPERATION FLOOD

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पसंद ऐसी जो शान बढ़ाये, देख सभी की चाह बन जाये!

जी हाँ। ऐसी अनमोल वस्तु जो है आपकी उत्कृष्ट पसंद की पहचान। देख जिसे सभी का मन ललचाये और चारों ओर जबरदस्त धूम मच जाये।

हम लाये हैं 24 कैरेट्स पंखा। केवल आपके लिए। क्योंकि आपको है सर्वश्रेष्ठ से लगाव।

आइवरी, आबनूसी तथा मदम भरे रंगों में। 1050, 1200 और 1400 मि मि के साईज में उपलब्ध।

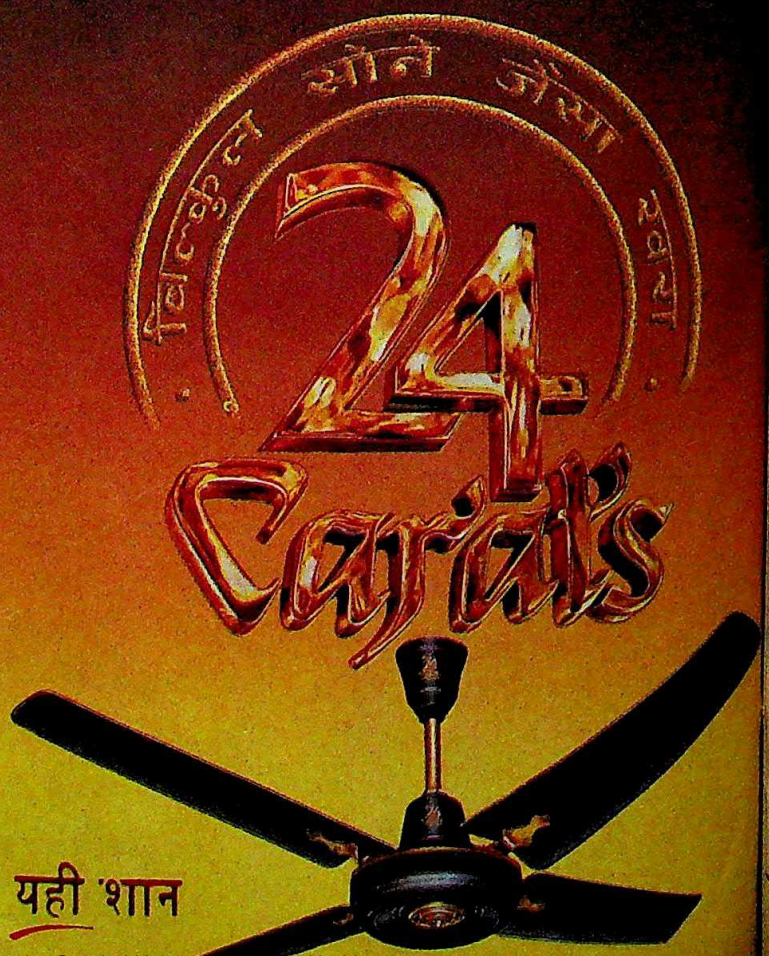

शानदार ज़िन्दगी की शान – यही शान

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कहानी संग्रह

कोई अलग पहचान नहीं

पर पात्रों में द्वंद्व के बावजूद जिजीविषा बाकी

यात्रा-मुक्त
राजी सेठ
नेशनल पब्लिशिंग हाउस,
23, दरियागंज, नई दिल्ली-2
पृष्ठ: 120, कीमत: 26 रुपए.

राजी सेठ की 12 साल की कथा यात्रा का चौथा (हिंदी में तीसरा) कहानी संग्रह 'यात्रा-मुक्त' व्यक्ति के आंतरिक संघर्षों की नौ कहानियों का संकलन है. 'यात्रा-मुक्त' की चिंतन प्रधान कहानियां अर्थवान होने के साथ-साथ उतनी ही संश्लिष्ट भी हैं—जैसे एक बिंदु से शुरू करके उसके चारों ओर मकड़ी का जाल-सा बुनते चले जाना. पुस्तक के जिल्द में लिखा—"अपने पूरेपन में ये विवरण से नहीं, संवेदन से बुनी हुई कहानियां हैं"—एकदम सही है. संभवत: इसीलिए कहानियों में काव्यात्मकता की झलक मिलती है. लेकिन यह खूबी नहीं कही जा सकती.

राजी सेठ के पात्र एक हाथ में ढाल और दूसरे में तलवार लेकर मैदान में उतरते हैं, खुद वार करते हैं और खुद ही रोकते रहते हैं. लेकिन गनीमत है इस लड़ाई के बाद वे निढाल होकर गिर नहीं जाते. उनमें जिजीविषा है और अंतत: वे द्वंद्व से बाहर निकलने का रास्ता तलाश लेते हैं.

सूक्ष्म बुनावट वाली इन कहानियों में प्रौढ़ता है. मानवीय पक्ष को उभारने की कोशिश भी साफ झलकती है. लेकिन कुल मिलाकर आंतरिक द्वंद्व ही प्रमुख है. बाहरी संसार से जूझते पात्र नहीं दिखाई देते. जो जूझते भी हैं उनके 'जूझने' में सपाटपन और ताप नहीं है. कहानियों का यही धीमा और ठंडा प्रवाह खटकता है.

'यात्रा-मुक्त' संग्रह की एकमात्र ऐसी कहानी कही जा सकती है जो खालिस अंतर्द्वंद्व का कुछ हद तक अपवाद है. इसमें किशना को हवेली वालों की 'जकड़' से मुक्त होने के लिए तड़पता दिखाया गया है. हवेली वालों की 'चाकरी' में अपना लड़कपन, जवानी और अधेड़पन होम कर देने वाले बापू को अपनी छोटी-छोटी खुशियों का गला घोंट कर हवेली के सुख-दुख का भागीदार बनता देख किशना (बेटा) गुलामी की घुटन को पहचानने लगता है और मुक्ति का मार्ग ढूंढ़ता है. वही पिता को भी गुलामी की दुर्गंध सूंघ पाता है. पर कोई तीखा-सीधा विद्रोह नहीं है. नपुंसक और बेरीढ़-से लगने वाले पात्र सोचते ज्यादा, करते कम हैं. कभी-कभी किशना के अंदर जरूर गरम लहर दौड़ती है—क्षणिक-सी.

बापू जिस हवेली में जीवन भर बंधुआ मजदूर की तरह जीने के लिए मजबूर हुए, उस हवेली के मालिक और मालकिन के प्रति लेखिका की पूरी सहानुभूति है. एक जगह लिखा है, "हवेली अब पहले वाला शीतल प्रवाह नहीं है जिसके किनारे बैठ सब अपने-अपने हिस्से की शीतलता पा लें...."

राजी सेठ की कहानियों में प्रौढ़ता है. मानवीय पक्ष को उभारने की कोशिश भी साफ झलकती है. लेकिन कुल मिलाकर आंतरिक द्वंद्व ही प्रमुख है. बाहरी संसार से जूझते पात्र नहीं दिखाई देते. जो जूझते भी हैं उनके जूझने में सपाटपन और ताप नहीं है. कहानियों का यह ठंडा प्रवाह खटकता है

यानी हवेली की शीतलता खत्म की है तरुण बाबू (छोटे मालिक) की उद्दंडता ने. तरुण बाबू न होते तो बापू का हवेली वालों की आजीवन गुलामी करना उचित होता?

संग्रह की पहली कहानी 'खेल' एक ऐसे फैक्टरी मालिक पर केंद्रित है जिसकी रक्तवाहिनी धमनियां अवरुद्ध हो चुकी हैं. वह लेखक जैसी 'बेमुरव्वत कौम' के आगे अपना दुखड़ा रोकर उसकी कहानी का पात्र नहीं बनना चाहता. अमेरिका में ऑपरेशन करा सकने की सामर्थ्य वाला उद्योगपति मरते दम तक लेखक के सामने अपना दुखड़ा न रोने (कमजोर न पड़ने) में कामयाब होता है. लेखिका ही बेहतर जान सकती हैं कि इस कहानी से वे हिंदी साहित्य को क्या देना चाहती हैं.

'यहां तक' खेलने-खाने के दिनों में परिवार के केंद्र में आने के लिए मजबूर हुए एक ऐसे पात्र की कहानी है जो बाद में अपने बेटे की परिवार के केंद्र में आने (और उसे परिधि में डालने) की तत्परता से आहत होकर उसके साथ मुठभेड़ की स्थिति में आ जाता है. कहानी अच्छी है. 'ढलान पर' कहानी में चारू किताबों, मुवक्किलों, मुकदमों के बोझ से दबे अपने पति की व्यस्तता को उसका 'नेगलेक्ट' करना मानकर अचानक एक दिन चित्रकार 'नैली' के साथ जा जुड़ती है. कथा-वस्तु सिर्फ इतनी ही है. कथा को चेतन (वकील) और चारू की एक शुभचिंतक महिला (दीदी) की जुबानी पेश कर लेखिका ने अपनी समृद्ध शैली का परिचय दिया है.

'तुम भी' ठीकठाक कहानी है. लेकिन कुछ अखरने वाले प्रसंग भी हैं. एक व्यक्ति को क्लर्क दिखाकर, फिर एक लाला के माल गोदाम का चौकीदार भी दिखाना और उसके भाई को डॉक्टरी की (वजीफे से ही सही) पढ़ाई करते दिखाना कुछ ऐसा मोह है जैसे उच्चमध्यवर्गीय और मध्यवर्गीय चरित्र को छोड़ा नहीं जा सकता और निम्नवर्गीय चरित्र (दयनीयता) को दिखाना मजबूरी है. 'मीलों लंबा पुल' में इसका और गहरा आभास होता है. पिता को हेड क्लर्क बना कर भी दयनीय बताना है और बेटे को 'अमेरिका' में भी दिखाना है. 'तुम भी' कहानी के क्लाइमेक्स में काफी जान है. लेकिन जहां (लेखिका के मोहवश) यात्रा-मुक्त के मामूली समझ वाले पात्र भी अंग्रेजी में सोचते हैं, वहीं डॉक्टरी पढ़ रहा देबू शास्त्र को 'शास्तर' और नायक (क्लर्क) पुण्य को 'पुन्न' कहता है. उन दोनों के बीच साधारण कहानी है. परिवार में बीमार को सहानुभूति देने के बजाय बोझ समझा जाता है, यह नई थीम नहीं है. कुल मिलाकर 'यात्रा-मुक्त' ऐसी कहानियों का संकलन नहीं है जो कोई अलग पहचान बना पाए. संग्रह पढ़कर पाठक एक गहरे समुंदर में गोते खाकर बाहर निकल आने का अनुभव ले सकते हैं. हठात-से 'कहीं' चोट करने वाला कुछ नहीं है.

—राकेश तिवारी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उपन्यास

त्रासदियों का एकांगी चित्रण

शांति और आपसी सौहार्द्र के लिए छटपटाते परिवारों की व्यथा

सभै घट राम बोले
गुरुबचन सिंह
अभिव्यंजना प्रकाशन,
नई दिल्ली
पृष्ठ: 184 कीमत: 35 रु.

गुरुबचन सिंह हिंदी और उर्दू में लिखने वाले जाने-पहचाने कथाकार हैं और उन्होंने अपना ताजा उपन्यास पंजाब की पृष्ठभूमि पर लिखा है जिसमें ताजा त्रासदियों को रेखांकित करने के लिए बीच-बीच में उन्होंने भारत विभाजन की घटनाओं का उल्लेख किया है. उनकी कोशिश यही रही है कि वे हर स्तर पर विभाजन की ज्यादतियों के मुकाबले पंजाब की आज की स्थितियों को और अधिक त्रासद सिद्ध करें. इस पर विवाद हो सकता है कि स्थितियां तब ज्यादा गड़बड़ थीं या आज हैं पर उन्होंने एक परिवार के जिस कष्ट को उभारा है उससे किसी के भी भीतर एक फांस-सी चुभती महसूस होती है.

देश के विभाजन के समय अनाथ हो गई बालिका का, उसे पालने वाले एक परिवार के ही लड़के से विवाह होना और बच्चे होने के बाद उसका विधवा होना. पहले बच्चे पालने का संघर्ष और फिर समाज के दो वर्गों में बढ़ते विद्वेष की चिंगारियों से उसके निजी परिवार में दिन-ब-दिन बढ़ती टूटन का कहीं न रुकने वाला सिलसिला, सब कुछ उसे अपने ही देश में बेगाना होने का एहसास कराता है. विधवा दुर्गा देवी का बड़ा बेटा सिख है और बाकी दो बेटे तथा एक दामाद हिंदू है. ऑपरेशन ब्लू स्टार के कुछ पूर्व से शुरू होने वाली यह कथा तत्कालीन प्रधानमंत्री की हत्या की प्रतिक्रिया में हुई घटनाओं के बाद तक की त्रासदियों की गवाही देती है.

पंजाब के हर जिले में दो वर्गों में आपसी घृणा, विद्वेष और शक का बीज और किसी ने नहीं राजनीति ने बोया है. लेखक की यह राय हर क्षेत्र में आपसी फूट के मूल कारणों की ओर इंगित भी है. अलगाव की आंधी के चलते हुए भी दुर्गावती चाहती हैं—प्रेम का वही पहले जैसा वातावरण.

उपन्यास में जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है यह वही है कि यह पूरी घृणा उन लोगों के बीच पैदा हो रही है जिनके रिश्ते खून के और बेटी-रोटी के हैं. एक ओर कट्टर सिख और उग्रवादी हैं तो दूसरी ओर हिंदुत्व को खतरा महसूस करते रक्तपात पर उतारू हिंदू. इस सबके पीछे एक साजिश है जिसके तहत लोगों को कूटनीतिक ढंग से बरगलाया जा रहा है और एक-दूसरे को मिटा देने के लिए तैयार किया जा रहा है. परिणाम यह होता है कि प्रेम और सद्भाव का वातावरण बनाने की कोशिश में लगे लोग भी बागी बनने पर मजबूर होते हैं. अलगाव की आंधी से दुखी लोग भी हिंसा को अपना लेते हैं.

"क्या हमेशा कुछ मांगने वालों का दमन करना पड़ता है? दूर बैठे लोग क्या जानें कि लोगों का आपस का कितना भाईचारा है? और दमन से कैसे सामाजिक रिश्ते टूटते हैं?... स्वार्थी लोग सत्ता और कुर्सी के लालच में इन रिश्तों पर हमेशा प्रहार करते हैं"

'सभै घट राम बोले' से

अंततः एक ही मां के जन्मे, एक ही खून के अंश कभी न पटने वाली अलगाव की खाई के दो किनारे बन जाते हैं.

लेखक का यह उपन्यास अलगाव की आंच में तपते पंजाब के परिवारों की संवेदनाओं से जुड़ी एक कथा जरूर है इसे दस्तावेज नहीं कहा जा सकता. कारण कि, इस उपन्यास के मूल में जो परिवार है भले ही उसमें हिंदू और सिख दोनों ही पात्र हैं पर इसमें सिखों की सहिष्णुता, उनकी धार्मिक पवित्रता, धार्मिक स्थानों पर सरकारी अतिक्रमण का दर्द, हिंदुओं के मुहल्ले में सिखों के प्रवेश पर शक का वातावरण और सरकार से उनके कुछ मांगने पर सरकार द्वारा दमन का रास्ता अपनाए जाने की जो बातें उपन्यास में उभरती हैं उसके मुकाबले हिंदुओं पर इस दौर में जो कुछ गुजरी उसका उल्लेख न के बराबर है. इस तरह कट्टर हिंदुओं के शस्त्र उठाने की बातें तो हुई हैं पर उग्रवादियों द्वारा की जाने वाली विनाशलीला की नहीं. इसी प्रकार अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की ज्यादतियों का भी हल्का-सा संकेत उपन्यास में है. गुरुबचन सिंह स्वयं सिख हैं और स्वाभाविक रूप से सिखों की धार्मिक प्रवृत्तियों और रीति-रिवाजों से उनका गहरा वास्ता है. शायद वे हिंदुओं की उन प्रवृत्तियों का उतना गहरा अध्ययन नहीं कर सके हैं. इसलिए अनेक स्थलों पर उपन्यास के एकांगी होने का बोध होता है. इसी तरह खुले तौर पर सेना पर कर्फ्यू के दौरान घूसखोरी, लूटपाट और बलात्कार के आरोपों पर भी लोगों को आपत्ति हो सकती है. युद्ध में तो कई बार सेनाएं ऐसा करती हैं पर पंजाब में भी ऐसा हुआ यह कहना हर कर्फ्यू लगने वाली फौज के व्यवहार से मेल नहीं खाता. उपन्यास के अंतिम अंश में कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जिनके न होने से भी उपन्यास अधूरा नहीं रहता.

"संसार में ऐसे लोग जन्म ले लेते हैं जब वह मर जाते हैं तो भी अपने पीछे ऐसी स्थिति, ऐसा खूनी माहौल छोड़ जाते हैं कि लोगों का नाहक खून बहता रहता है. ऐसी आत्माओं को क्या कहा जाएगा."

इस सबके बावजूद कुल मिलाकर उपन्यास पंजाब में हुई घटनाओं और वहां शांति तथा आपसी सौहार्द्र के लिए छटपटाते परिवारों का मार्मिक चित्रण करता है. उपन्यास में सरकार और राजनीति के प्रति पंजाब में व्याप्त विरोध का भाव भी स्पष्ट रूप से उभरता है. लेखक यह कहने में भी सफल हुआ है कि किसी तरह की मांग करने पर सरकार द्वारा दमन का रास्ता अपनाए जाने से रक्तपात होने के साथ-साथ उत्पादन और अमन-चैन की हानि अवश्यंभावी है. एक तरह से इस उपन्यास में इंगित बातों से सरकार के लिए पंजाब में अमन लाने का मार्ग भी प्रशस्त होता है. पर एकांगी होने के कारण पाठकों को इसे एक कथा के रूप में ही पढ़ना चाहिए, इसकी कमियों के प्रति सचेष्ट रहकर.

—विजयकिशोर मानव

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अलंकरण अब आसान

आसान अब और भी आसान

अब पेश है

DURATUFF

टिकाऊ और मज़बूत बोर्ड

एक बहु-उपयोगी बोर्ड, जिसने वर्षों से विदेशी घरों को नया आकर्षक रूप दिया, अब भारत में भी मिल रहा है।

...र भारत में ग्राहकों का सपना साकार ...लिए मीडियम डेनसिटी फाइबर बोर्ड ...पेश है! ड्यूराटफ, इस तरह बना है ...जीवनधारा को एक नया आयाम ...आयामी यह उपयोगी बोर्ड वर्षों से ...घर का नकशा बदलने के बाद अब इस ...भी मकानों में नई जान डालने को ...कम्प्यूटर प्रॉसेस्ड टेकनोलॉजी के जरिये ...राटफ, प्लाइवुड और पार्टिकल बोर्डों से ...तर है।

...मनचाही कोई भी चीज़ बनाइये: ...मेनटेड और प्लेन में उपलब्ध ड्यूराटफ अधिक मज़बूत, दोनों ओर चिकनी सतह और मोटाई एक-सी। किसी भी दिशा में कटाई, उभरी डिजाइन और मनपसंद किसी भी आकार की चीज़ बनाने के लिये ड्यूराटफ लाजवाब है। लूईस XIV चेयर या स्कैण्डिनेवियन टेबल, ड्यूराटफ से बनाना महज आसान है! सिर्फ फर्नीचर ही नहीं ड्यूराटफ से दरवाज़े, पार्टिशन, जमीन की सतह या ताक आदि शानदार बने, बढ़िया बने।

कभी खराब न होने वाला बोर्ड: दबाव डालिये, पीटिये, ठोकर मारिये—ड्यूराटफ पर फिर भी कोई खरोंच नहीं। दीमक से बचाव की ज़रूरत नहीं। नमी के वातावरण में भी यह खपच्चियां उतरने का बखूबी मुकाबला करे। कारण स्पष्ट है कि यह ज्यादा से ज्यादा अरसे तक टिकने और हमेशा साथ निभाने के लिए ही बना है।

आपके पैसों की सही कीमत चुकाने वाला बोर्ड: मामूली खर्च में ड्यूराटफ आपको देगा लकड़ी का विलासपूर्ण काम, क्योंकि ड्यूराटफ काम को आसान बनाये और वक्त भी घटाये। मिसाल के तौर पर कीमती बीडिंग, लिपिंग आदि ड्यूराटफ में ज़रूरत नहीं होतीं। अन्य बोर्डों की तरह ड्यूराटफ के ग्रेन पर कटाई करने से यह चटखता नहीं।

ड्यूराटफ की नवीनतम दुनिया में कदम रखिये। ड्यूराटफ आसान और व्यावहारिक है। इसमें आप आराम व शानदार जिन्दगी जी सकेंगे। सचमुच, ड्यूराटफ आपके ज़माने का एक ज़बरदस्त इन्क़लाब है!

मुफ़्त पुस्तिका के लिये लिखिये:

मंगलम टिम्बर प्रोडक्ट्स लि.

१५ इंडिया एक्सचेंज प्लेस, तीसरी मंज़िल
कलकत्ता ७०० ००१
फोन: २०-१३६८/४१७८/४१०७

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

ड्यूराटफ—देखिये इससे चीजें बनती हैं कैसे

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आम तौर पर ख़रीदार सूटकेसों में चार चीज़ें देखते हैं.
लेकिन 'सफ़ारी' देखते हैं ८६ और.

(गुप्त)
Madadgar
agenines
Rly. Road
Haridwar
U.P.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आम तौर पर ख़रीदार सूटकेस लेते समय सिर्फ़ उसका रंगरूप, आकार, साइज़ और क़ीमत ही देखते हैं.

और ख़रीदने के बाद ही जान पाते हैं कि और भी कई ऐसी बातें हैं जो उन्हें देख लेनी चाहिएं थीं.

लेकिन सफ़ारी खरीदने पर ऐसा नहीं होता.

क्योंकि ख़रीदार के देखने से पहले ही हर सफ़ारी में ९० अलग-अलग बातों की जांच-परख की जा चुकी होती है.

इस बात की तसल्ली के लिए कि आपके सफ़ारी में किसी तरह की ख़ामी न रह जाए.

लेकिन क्वालिटी का मतलब सिर्फ़ जांच करना ही नहीं है. सूटकेस का टिकाऊ होना और उसमें सुविधाओं का होना भी बहुत ज़रूरी है.

जैसे तालों को ही लीजिए, हर सफ़ारी का बीचवाला ताला ६ लीवर का वॉल्ट-ताला होता है जो कि दूसरे सूटकेसों में इस्तेमाल होनेवाले ४ लीवर या ५ लीवर के मामूली तालों से, १० गुना ज़्यादा मज़बूत होता है.

या फिर कब्ज़ों को बारीकी से देखिए. सफ़ारी के कब्ज़े क्रोमियम प्लेटेड होते हैं लिहाज़ा उनमें जंग नहीं लगता और वे ज़्यादा चलते हैं जबकि दूसरे सूटकेसों में ये ज़िंक-प्लेटेड होते हैं. ऐसी कितनी ही छोटी-छोटी बातें हैं और ये सब एक ही बात साबित करती हैं.

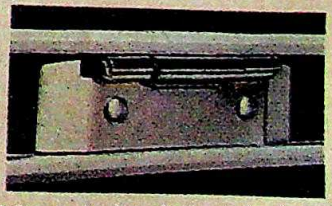

सारी परेशानियां हम उठा लेते हैं ताकि आप परेशान न हों.

भरी हैं इसमें सैकड़ों खूबियां.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

◆ बांबे डाइंग के मालिक नुसली वाडिया की पत्नी होने के नाते **मॉरीन वाडिया** के नवीनतम शगूफे से कपनी को यकीनन लाभ हुआ होगा. 30 मार्च के दिन मॉरीन के नेतृत्व में एक फैशन-म्यूजिकल यात्रा की शुरुआत अहमदाबाद से हुई जिसमें रॉक संगीत और फैशन शो का मिश्रण पेश किया गया. बांबे डाइंग के रंग-बिरंगे कपड़ों में रॉक संगीत की धुन पर थिरकते मॉडलो ने माहौल को रंग और मस्ती में सराबोर कर दिया. मॉरीन का कहना था, "इस यात्रा का उद्देश्य फैशन को आम लोगों तक ले जाना और युवा लोगों को साफ-सुथरा मनोरंजन प्रदान करना है." रिलायंस कंपनी के साथ चली खींचतान के बाद यकीनन साफ-सुथरेपन की जरूरत बढ़ी है.

◆ ओलंपिक मुकाबलों में अगर कोई शांति की दौड़ का मेडल जीत ले तो? बंबई की विज्ञापन दुनिया के **गुरुनाथ भाडेकर**

(29) और **संजय सिपाहीमलानी** (25) ने यही कर दिखाया है. 'टाइम' पत्रिका ने ओलंपिक प्रतीक चिन्ह के लिए एक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया.

वाडिया: नया शगूफा

उनकी साझी प्रविष्टि में एक फाख्ता को ओलंपिक मशाल के रूप में दर्शाया गया था और शीर्षक का अर्थ हिंदी में कुछ इस तरह था: "शांति की मशाल—मेडल से ज्यादा कीमती और विजय के मुकाबले बेमिसाल" उन्हें दूसरा स्थान मिला. सिओल ओलंपिक के दौरान इसे पत्रिका के एशिया संस्करण में प्रकाशित भी किया जाएगा. खुशी से झूमते गुरुनाथ का कहना था, "हमारे लिए तो यह अंतरराष्ट्रीय सम्मान जैसा है."

◆ भारत-फ्रांस सांस्कृतिक संबधों के मामले में **एलायंस-फ्रांसे संस्था** का योगदान 50 बरस से चलता आ रहा है. पिछले सप्ताह ठेठ फ्रांसीसी अंदाज में इस बात को एक नाटक के माध्यम से विशेष अभिव्यक्ति दी गई. फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े और भारतीय कलाकारों द्वारा पेश किए गए इस द्विभाषी नाटक के बारे में केंद्र के मुखिया **पैट्रिक बेक** की टिप्पणी थी, "फ्रांसीसी ठप्पे वाला यह नाटक एक विशुद्ध 'मेड इन इंडिया' प्रस्तुति है." अपने शौकिया कलाकारों की प्रशंसा में नाटक के पटकथा लेखक और निर्देशक ज्यां जैक्यू बेलो का कहना था, "उन्हें नाटक की बारीकियों की पूरी समझ है." गर्मियों में यह मंडली पेरिस की एक प्रतियोगिता में इस नाटक को पेश करेगी. बात बनी तो नाटक अगले साल एक विशेष समारोह में खेला जाएगा.

नाममः भोजानी

संस्कृति के दूत

भाडेकर और सिपाहीमलानी: सफलता

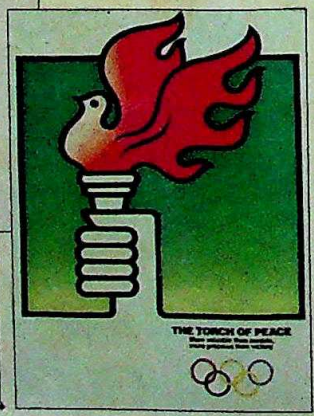

◆ पिछले दिनों तबले और पेंटिंग की जुगलबंदी के बाद बंबई में पेंटिंग और कपड़ों के फैशन की जुगलबंदी ने रंग जमाया. मफतलाल टेक्सटाइल घराने की सदस्या और शौक से डिजाइनर **अनुराधा मफतलाल** (27) ने देसी अंदाज में 'आर्ट-वियर' का झंडा बुलंद किया. उन्होंने अपने डिजाइन किए कपड़ों पर मंजीत बावा, सुरुचि चांद और जगदीश जैसे कलाकारों से पेंटिंग बनवाई और एक बिक्री नुमाइश में पेश कर दी. इस नए फैशन के बारे में उनकी पार्टनर **बीना किलाचंद** (32) का कहना था, "इन कपड़ों को पहनना ऐसा है मानो आप अपनी पीठ पर कोई पेंटिंग लिये चल रहे हों." और पीठ पर पेंटिंग ढोने के शौकीनों ने 2500 रुपए के हिसाब से सभी पोशाकें खरीद लीं.

किलाचंद और मफतलाल

◆ 1935 मॉडल की 500 सीसी नार्टन मोटरसाइकिल को नौगजिया (नौवारी) मराठी साड़ी पहनकर कोई युवती चला रही हो तो? तो यह तय है कि वह 28 वर्षीया **निशा सुतरिया** ही होगी जिसने पिछले दिनों बंबई की पुरानी कार और मोटर साइकिल रैली में एक बार फिर अव्वल नंबर हासिल किया. इससे पहले ऐसी रैलियों में निशा तीन बार बंगाली वधू, सौराष्ट्री महिला और एक मुस्लिम युवती की वेशभूषाओं के लिए पहला इनाम जीत चुकी हैं. पेशे से फार्मासिस्ट निशा का रैलियों के बारे में कहना है, "यह मजेदार काम है. इसमें बसा रोमांच मुझे बहुत अच्छा लगता है." वे हिमालय कार रैली में भी चार बार हिस्सा ले चुकी हैं और कहती हैं, "10 साल पहले जब मैंने मोटर साइकिल चलाना शुरू किया तब लोग कई तरह के फिकरे कसते थे. पर अब मुझे इनकी परवाह नहीं."

निशा: सफलता का नशा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वादों की विरासत

तड़क-भड़क वाले थलसेनाध्यक्ष जनरल ज्ञानस्वामी सुंदरजी पिछले पखवाड़े पदमुक्त ए. अपने पीछे वे सेना के इतिहास का सबसे ादास्पद दौर छोड़ गए हैं. उनके कार्यकाल हुए महत्वपूर्ण एवं दूरगामी परिवर्तनों का ेष और साथ में उनसे हुई विशेष बातचीत :

आवरण कथा.....50

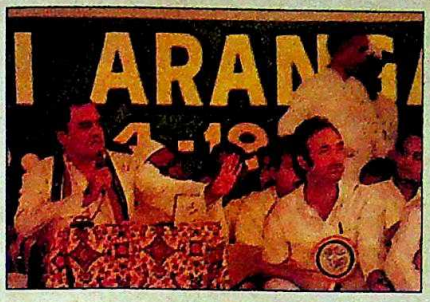

नेता के आगे नतमस्तक

घोटालों और असंतोष से घिरी पार्टी और उसके नेता की घटती साख के मद्देनजर मद्रास में इंका महासमिति का अधिवेशन संगठन में आत्मविश्वास लौटाने की ही एक कवायद थी. पार्टी की छवि निखारने की इस कोशिश में जी-हुजूरियों की फिर बन आई.

विशेष लेख.....22

क-साफ दिखाने की कोशिश

ोफोर्स घोटाले की जांच कर रही संसदीय मेटी ने अपनी रिपोर्ट दे तो दी लेकिन 'हिंदू' खबार में कुछ नए दस्तावेजों के प्रकाशन ने स रिपोर्ट को बेनकाब कर दिया. इस मामले ी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं विन चड्ढा. उनसे ातचीत और मामले पर विस्तृत रिपोर्ट.

खास रपट.....29

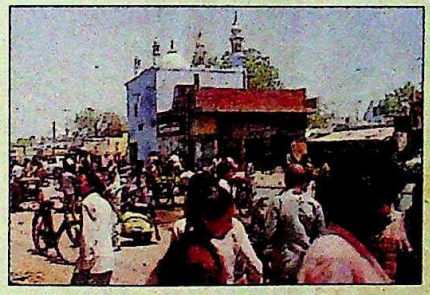

दंगे का दंश और दर्द

भीषण सांप्रदायिक दंगों के साल भर बाद ही मेरठ में पिछले पखवाड़े हालात फिर बिगड़ उठे. यहां के निवासियों के मन में भय और अविश्वास हालांकि स्थायी जड़ें जमा चुका है पर राज्य सरकार ने भी हिंसा पर काबू पाने के लिए कोई पहल नहीं की.

विशेष लेख.....76

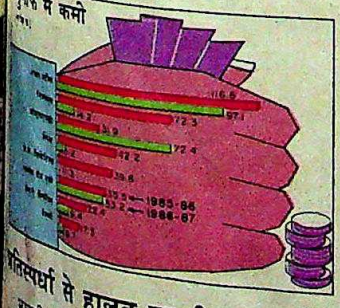

तिस्पर्धा से हालत पतली

ारतीय व्यवसाय जगत अब पहले जैसी ालत में नहीं रहा. प्रतिस्पर्धा बढ़ने के साथ कंपनियों को अब कम दाम में बेहतर उत्पाद देने ा लक्ष्य होना पड़ा है. उद्योग-क्षेत्र में सरकारी ीति का आकलन और उद्योगपतियों व ेक्षकों पर इसके असर की समीक्षा.

व्यापार.....80

उगते सूरज के देश में चकाचौंध

भारत महोत्सव अपनी सांस्कृतिक विरासत का प्रचार-प्रसार करने जापान में अजनबी लोगों के बीच जा पहुंचा. महोत्सव के बारे में मौके पर जाकर लिखी गई रिपोर्ट के साथ ही प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जापान और विएतनाम यात्राओं का विवरण.

जगबीती.....66

अगले पन्नों पर

कसौटी.....12
राजरंग.....14
तेवर.....19
हिंदोस्तां हमारा.....20
बीता पखवाड़ा.....21
विशेष लेख
इंका अधिवेशन : नेता के आगे नतमस्तक..22
खास रपट
बोफोर्स जांच :
पाक-साफ दिखाने की कोशिश.....29
आजकल
कर्नाटक : जन अदालत में.....36
बिहार : इंसाफ का शाही अंदाज.....37
महाराष्ट्र : न्यायमूर्ति की निंदा.....39
केरल : 'भक्त' मार्क्सवादी.....40
मध्य प्रदेश : निशाने पर अर्जुन.....41
गुजरात : 'होनहार' छात्र.....42
आखिरी बात.....43
राज्य-दर्पण.....44
आवरण कथा
जनरल के. सुंदरजी :
विवादों की विरासत.....50
समाचार माध्यम
पंजाब : खतरों से घिरे अखबारनवीस.....63
विज्ञान चर्चा.....64
जगबीती
भारत महोत्सव :
उगते सूरज के देश में चकाचौंध.....66
राजीव की यात्रा :
सुहाने सफर की सफलता.....70
खास रपट :
अफगानिस्तान : फैसला बंदूकों से.....72
विशेष लेख
मेरठ : दंगे का दंश और दर्द.....76
व्यापार चक्र.....79
कारोबार
व्यवसाय जगत : स्पर्धा से हालत पतली....80
मेटल बॉक्स : भविष्य डिब्बे में.....85
खेत-खलिहान
अनाज : उपज बढ़ने पर भी टोटा.....88
टीवी
पाकिस्तानी सीरियल :
मनोरंजन के मोर्चे पर आगे.....90
खेलकूद
संतोष ट्राफी : बेजान, विवादास्पद स्पर्धा...93
विज्ञान
आईआरएस-1ए : खजानों पर खोजी नजर.94
स्वास्थ्य
डॉ. एम.सी. मोदी : खुदाई खिदमतगार.....99
अपराध
चंबल के डाकू गिरोह : छोटे पर शातिर.100
सुरताल
भैरव से सोहनी : अबलाओं का बल.....101
रंगमंच
रानावि दीक्षांत समारोह :
इतिहास दोहराने के बहाने.....102
किताबें.....107
चर्चित चेहरे.....112

आवरण : सवान सिंह

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

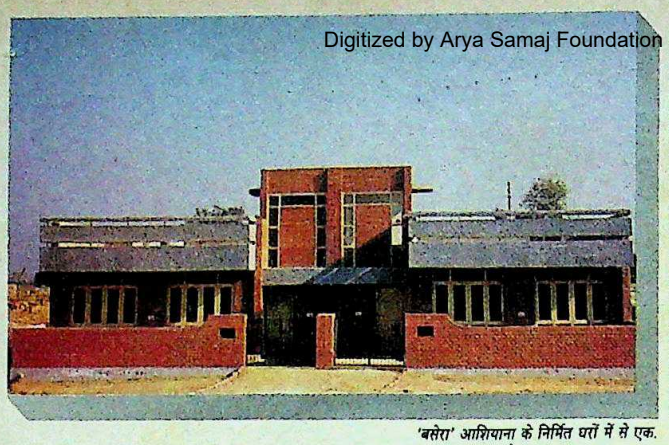

'बसेरा' आशियाना के निर्मित घरों में से एक.

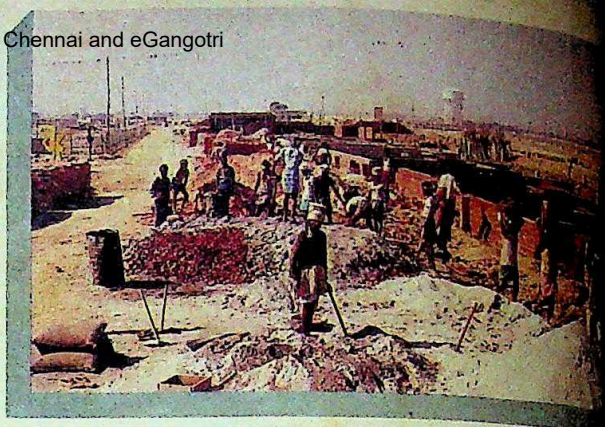

300 घरों का निर्माण [illegible]

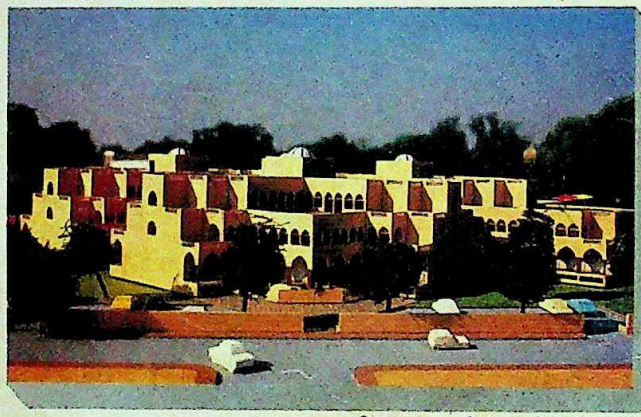

आशियाना का अत्याधुनिक व्यावसायिक परिसर–'खज़ाना'

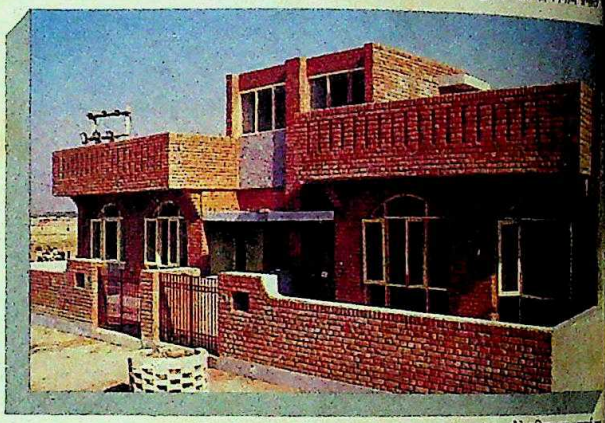

'आरज़ू' – छोटे परिवार का [illegible]

एक खूबसूरत लघुनगर जिसमें है, हर पसन्द हर ज़रुरत के लिए घर.

अन्सल्स

आशियाना

लखनऊ

आशियाना. यही है वह लघुनगर जिसमें आपके सपनों का घर भी है. एक सम्पूर्ण साकार रुप में. ठीक आपकी ज़रुरत के अनुसार, आपकी आर्थिक क्षमता के अनुसार.

आपके चुनाव के लिए है विभिन्न प्रकार के निर्मित घर. शान-ए- अवध, गुलशन और एक्सपैन्डेबल होम्स (विस्तार योग्य घर)– अन्जुमन, बसेरा और आरज़ू. वे घर जो आपकी आज की ज़रुरतों को पूरा करते हैं और भविष्य की ज़रुरतों के अनुसार नीचे तथा ऊपर 3 मंजिलों तक बढ़ाए जा सकते हैं. हर एक के साथ लॉन और किचन गार्डन, हर घर बेहतरीन निर्माण तकनीक की बेमिसाल तस्वीर. सभी कुछ एक स्वस्थ, हरे-भरे वातावरण के बीच. आइये, और आशियाना के निर्मित घरों को देखिए, आप स्वयं जान जाएंगे कि अन्सल्स आपके लिए किस किस्म की जीवन-शैली का निर्माण कर रहे हैं, आशियाना के रुप में. 1990 में आपके स्वागत के लिए, आपके प्रवेश के लिए. इसलिए शीघ्र ही अपना मनपसन्द घर बुक कीजिए और निश्चिंत हो जाइये.

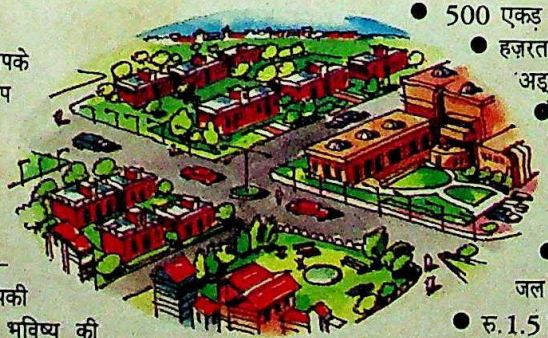

- प्लॉटों पर कब्जा 1988 में और निर्मित घरों पर 1989 में, विभिन्न चरणों में.
- तेज़ी से विकसित हो रहा है– 10 नमूने के घर तैयार, 300 घरों का निर्माण पूर्णता की ओर.
- 500 एकड़ पर 20,000 परिवारों के लिए लघुनगर.
- हज़रतगंज से मात्र 7 किमी, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, बस स्टेण्ड समीप ही.
- 5 प्रकार के निर्मित घर तथा 6 आकार में प्लॉट उपलब्ध.
- आधुनिक सुविधाएं–स्कूल, अस्पताल, क्लब, शॉपिंग सेन्टर 'खज़ाना,' पार्क आदि.
- नागरिक सुविधाएं- मल निकास व्यवस्था, जल प्रदाय, बिजली आदि.
- रु. 1.5 लाख तक के आवासीय ऋण भी उपलब्ध.
- सुविधाजनक बुकिंग राशि–शेष आसाना ब्याज़ मुक्त किस्तों में

विस्तृत विवरण के लिए सम्पर्क करें, लिखें

अन्सल हाउसिंग फाइनेन्स एण्ड लीज़िंग कं० लि०

2, चायना बाजार रोड (तुलसी सिनेमा के पीछे) लखनऊ -226 001 फोन: 48554.

पंजीकृत कार्यालय: 115, अन्सल भवन, 16, कस्तूरबा गांधी मार्ग नई दिल्ली -110 001, फोन: 331-7015 टेलेक्स: 031-62626 ANSL IN.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ड्यूराटफ इनक़लाब।

क्या आप खुश नहीं कि यह इनक़लाब आपके दौर में आया?

यह है ड्यूराटफ का इनक़लाब: *ड्यूराटफ—एक बहु-उपयोगी बोर्ड, जो वर्षों से विदेशों में दफ्तरों का नकशा बदलता आ रहा है, अब आपके दफ्तर की कायापलट के लिए हर पल तैयार! क्योंकि कम्प्यूटर प्रोसेस्ड टेक्नोलॉजी के जरिये बनाया गया ड्यूराटफ, प्लाइवुड और पार्टिकल बोर्डों से कहीं बेहतर है।*

हर काम को आसान बनाने वाला बोर्ड: *ड्यूराटफ से काम करना बिलकुल आसान है क्योंकि, यह लकड़ी के काम को आसान बनाते हुए आपके पैसों की भारी बचत और साथ ही समय की भी बचत करता है। उदाहरण के तौर पर एक स्मार्ट एग्ज़िक्यूटिव का डेस्क ड्यूराटफ से बनाना महज आसान है। एधेसिव के बिना जोड़िये स्क्रू और कांटी से, और इसके अलावा एज बैंडिंग या लिपिंग की कोई ज़रूरत नहीं।*

कभी खराब न होने वाला बोर्ड: *ड्यूराटफ कॉन्फरेन्स रूम टेबल को ही लीजिये। इसे ठोंकिये या जलती हुई तीली इस पर फेंकिये कोई असर नहीं—ड्यूराटफ ज्यों का त्यों बना रहेगा। नमी की हालत में भी यह फूलता नहीं। दफ्तरों के लिए ड्यूराटफ पर खर्च करना सर्वथा उपयुक्त होगा।*

जैसा जी चाहे इस्तेमाल कीजिए: *खूबसूरत और किफायती पार्टिशन के लिए दो-तरफा लैमिनेशनयुक्त ड्यूराटफ, उभरी डिजाइन के साइड बोर्ड, कैबिनेट और स्कैण्डिनेवियन ऑफिस यूनिट के लिए लाजवाब है।*

लैमिनेट की वृहत् शृंखला अथवा प्लेन में उपलब्ध ड्यूराटफ अधिक मजबूत, दोनों ओर चिकनी सतह और एक-जैसी मोटाई तथा १८ फीट तक की विभिन्न साइज़ों व २ इंच तक की मोटाई में मिलता है।

ड्यूराटफ की नई दुनिया में कदम रखिये। ड्यूराटफ आसान और व्यावहारिक है। इसमें आप आराम व शानदार जिन्दगी जी सकेंगे। सचमुच, ड्यूराटफ आपके ज़माने का एक ज़बरदस्त इनक़लाब है।

DURATUFF
टिकाऊ और मज़बूत बोर्ड

देखिये इसे, चीज़ें बनती हैं कैसे

मुफ़्त पुस्तिका के लिये लिखिये:

मंगलम टिम्बर प्रोडक्टस लि.
१५ इंडिया एक्सचेंज प्लेस, तीसरी मंज़िल
कलकत्ता ७०० ००१, फोन: २०-१३६८/४१७८/४१०७

HTA 3256

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इंडिया टुडे
पूरा समाचार पत्रिका

अंक 13, 1-15 मई, 1988

प्रधान संपादक: अरुण पुरी
वरिष्ठ संपादक: प्रभु चावला

लिविंग मीडिया इंडिया प्रा. लि., एफ-14, कंपिटेंट हाउस, कनाट प्लेस, नई दिल्ली के लिए अरुण पुरी द्वारा संपादित और स्थापित तथा थॉमसन प्रेस इंडिया लि. फरीदाबाद, हरियाणा में मुद्रित.

संपादकीय कार्यालय:
लिविंग मीडिया इंडिया प्रा. लि., एफ-14/15, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001. फोन: 331 5801-4, टेलेक्स: 31-61245 INTO IN, तार: लिवमीडिया नई दिल्ली.

मुख्य सर्कुलेशन कार्यालय:
इंडिया टुडे सर्कुलेशन मैनेजर, एफ-14, कंपिटेंट हाउस, कनाट प्लेस, सिंधिया सर्कल, नई दिल्ली-110001. फोन: 3313076-8, टेलेक्स: 31-62634 INTO IN, तार: सर्कुलेट, नई दिल्ली.

मुख्य विज्ञापन कार्यालय:
20 ए और बी, जॉली मेकर चैंबर-2, नरीमन पाइंट, बंबई-400021. फोन: 2026152, 2029326, 2029435, टेलेक्स: 11-5373 THOM IN, तार: लिवमीडिया बंबई.

क्षेत्रीय विज्ञापन कार्यालय:
के-9, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001, फोन: 3325378, 3323576, 3321323, 3321273; टेलेक्स: 31-62124 THOM IN, तार: लिवमीडिया, नई दिल्ली; फागुन चैंबर्स, 26 कमांडर-इन-चीफ रोड, मद्रास-600105. फोन: 477188, 477770, टेलेक्स: 041-6177 INTO IN, तार: लिवमीडिया, मद्रास; 74/1, मैट मार्क्स रोड, बंगलूर-560001. फोन: 568448, 579037, 579089. टेलेक्स: 0845-2217 INTO IN, तार: लिवमीडिया, बंगलूर; 12-सी, एस्प्लेनेड 46-सी, चौरंगी रोड, कलकत्ता-700016 फोन: 445398, 447726, टेलेक्स: 021-3138 INTO IN, तार: लिवइन-मीडिया, कलकत्ता.

कॉपीराइट 1984 लिविंग मीडिया इंडिया प्रा. लि. विश्व भर में सर्वाधिकार सुरक्षित. किसी भी रूप में सामग्री की पूर्ण प्रतिलिपि, इंडिया टुडे अनिमंत्रित प्रकाशन सामग्री को लौटाने की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता.

नेपाल में 6 रुपए

दांव पर सुरक्षा

आवरण कथा 'उलझनों में उलझा सच' (30 अप्रैल) पढ़कर महसूस हुआ कि सत्ता में बैठे लोग दलाली खाने के लिए देश की सुरक्षा को किस तरह दांव पर लगा देते हैं. सबको मालूम है कि जांच समितियां बिठाने का असली मकसद सच को और उलझाना ही है. जनता सच कभी नहीं जान पाएगी, लेकिन एक सचाई तो सामने आ ही गई है कि देश की सुरक्षा, अखंडता का जाप करके सत्ता में आने वाली 'क्लीन' सरकार का असली मुखौटा क्या है.

—रंजिदर कुमार शुक्ला, ऊना (हि.प्र.)

■ प्रधानमंत्री का यह दावा हास्यास्पद ही लगता है कि 'कमीशन खाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.' क्योंकि सरकार की एक-एक हरकत इस बात की पुष्टि करती है कि सरकार का परोक्ष या अपरोक्ष रूप में घोटाले में हाथ जरूर है. अन्यथा जांच समिति में अपनी सहयोगी पार्टी के सदस्यों को भरना, सबूत पाने के हर मौके को हाथ से निकाल देना, सौदे का रहस्य जानने वालों को परेशान करना किस बात का सबूत है?

—शरद जाजू, नई दिल्ली

■ पता नहीं ऐसे कितने ही सौदे पहले होते रहे होंगे और देश की सुरक्षा के नाम पर हथियारों में दलाली खाई गई होगी. लगता है कि हथियार देश की सुरक्षा से ज्यादा कमीशन खाने के लिए खरीदे जाते हैं.

—सुनीता सैनी, नई दिल्ली

छलावा ही रहेगी

कसौटी के अंतर्गत 'एकता का छलावा' (30 अप्रैल) पढ़कर दुख तो हुआ ही, विपक्ष की कलाबाजियों पर हंसी भी आई. यह भारत का दुर्भाग्य (और इंका का सौभाग्य) ही है कि मजबूत विपक्ष के अभाव में जनता द्वारा चुनी गई सरकार जनमत की ही अवहेलना करके अधिनायकवादी रुख अख्तियार कर लेती है.

—निर्मला गर्ग, डेरावस्सी (पंजाब)

■ विपक्ष की एकता शायद छलावा ही रहेगी. वक्त ने उन्हें कई बार मौके दिए लेकिन हर मौका उन्होंने आपसी कलह, ईर्ष्या और द्वेष के कारण गंवा दिया. आपने अपने लेख में बिल्कुल ठीक कहा है, "यदि ऐसे प्रतिद्वंद्वी हों तो राजीव की पार्टी को दोस्तों की क्या जरूरत?"

—ओमदत्त, करनाल (हरियाणा)

हल नहीं चाहते

मुनि सुशील कुमार से मुलाकात 'कुछ लोग शांति नहीं चाहते' (30 अप्रैल) से साफ जाहिर है कि सरकार खुद ही पंजाब समस्या को हल नहीं करना चाहती. वरना राष्ट्रपति शासन, व्यापक अधिकारों और इतने पुलिस बल के बावजूद क्या मुट्ठीभर आतंकवादियों पर काबू नहीं पाया जा सकता.

—संगीता, जालंधर (पंजाब)

आचरण भी बदले

'देसीपन का चढ़ता बुखार' (30 अप्रैल) लेख रोचक भी लगा और सामयिक भी. देश की नई पीढ़ी अपनी संस्कृति पर गर्व करना सीखे यह निश्चय ही शुभ संकेत है लेकिन पहनावे के साथ-साथ आचरण और व्यवहार में भी देसीपन जरूरी है जो कि कहीं नजर नहीं आता. ठेठ ग्रामीण पहनावे में सिगरेट का धुंआ छोड़ती लड़की और पाजामे-कुर्ते और जवाहर जैकेट में डिस्को की ओर जाते लड़के क्या विसंगति पैदा नहीं करते?

—शारदा, देवलाली (महाराष्ट्र)

संतोष की बात

प्रतिरक्षा स्तंभ के अंतर्गत 'शुरुआत ही हैरतअंगेज' (30 अप्रैल) में नवगठित कमांडो फोर्स 'आईएमएसएफ' की सफलता पढ़कर संतोष हुआ कि भारतीय सेना अब हर संकट का सामना करने में सक्षम है. वैसे 1971 की लड़ाई में वह अपना रणकौशल सिद्ध कर ही चुकी है. उम्मीद की जानी चाहिए कि आईएमएसएफ उसकी प्रतिष्ठा और बढ़ाएगी. साथ ही देश की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी.

—आर.एम. शर्मा, आगरा (उ.प्र.)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मूल्यों के पतन का संकेत

आवरण कथा 'किस्सा राजीव की कुर्सी पलटने की कोशिश का' (15 अप्रैल) पढ़कर लगा कि इस प्रजातांत्रिक देश में अवसरवादी एवं स्वार्थी राजनीति के कारण नैतिक मूल्यों का पतन हो चुका है. हमारे पूर्व राष्ट्रपति अपनी महत्वाकांक्षा के कारण देश पर एक बड़े संकट के श्रेयधारक बनते-बनते रह गए. और जब उन्हें लगा कि उनका महत्व कम होता जा रहा है तो एक नया शगूफा छोड़कर पुनः विवादों के केंद्र तो बने ही, सरकार के लिए नई परेशानी भी उन्होंने खड़ी कर दी.

—**सुरेंद्र तिवारी,** बीना (म.प्र.)

■ सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित होकर व्यक्ति इतनी बचकाना हरकत कर सकता है इसका विश्वास नहीं होता. ज्ञानी जी ने सचमुच ही डॉ. राजेंद्र प्रसाद, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉ. जाकिर हुसैन की सम्मानित परंपरा को कलंकित किया है. राष्ट्रपति भवन त्यागने के बाद भी उन्होंने जो वक्तव्य दिए हैं वे दुखद ही नहीं, अशोभनीय भी हैं. —**सुरेशनंदन प्रसाद सिंह,** पोर्ट ब्लेयर (अंदमान निकोबार)

■ घटनाक्रम का पूरा विवरण पढ़कर महसूस हुआ कि पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव से पहले हिंदुस्तान की राजनीति में एक भूचाल आने वाला था जो किसी तरह टल गया. निस्संदेह ज्ञानी जैल सिंह आज तक के सर्वाधिक विवादास्पद राष्ट्रपति रहे हैं, चाहे वे पद पर रहे या रिटायर हो गए.

—**प्रमोद कुमार सिंह,** कष्टहारा (बिहार)

■ लेख पढ़कर यही लगा कि ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति पद तक तो पहुंच गए लेकिन उनमें विवेक का अभाव, अस्थिर नीति व अस्पष्ट विचार जैसी चारित्रिक कमियां कूट-कूटकर भरी हुई हैं.

—**अशोक कुमार उपाध्याय,** कटकड़ (राज.)

■ घटनाओं का दैनिक ब्यौरा पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव कमजोर करने की साजिश की जा रही थी. यदि ज्ञानी जी अपना उल्लू सीधा करने वाले कतिपय लोगों के बहकावे में आ जाते तो भारी अनर्थ हो जाता. किसी निर्वाचित प्रधानमंत्री को बरखास्त करने का कोई औचित्य नहीं, और संसद में उसका स्पष्ट बहुमत रहते तो बिल्कुल नहीं.

—**रामगोपाल खेतान,** बर्दवान (प. बंगाल)

■ लोकतंत्र की हत्या की इस साजिश में जो भूमिका पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की रही, उतना ही दोष प्रधानमंत्री राजीव गांधी का भी था. उन्होंने कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा की होंगी जिनकी वजह से प्रधानमंत्री की कुर्सी पलटने की साजिश की गई. घटनाओं की विवेचना साफ बताती है कि सत्ता की खातिर सभी का नैतिक पतन पराकाष्ठा की सीमा तक पहुंच चुका था. इन घटनाओं से राजीव गांधी की छवि और अधिक दागदार हुई है.

—**प्रकाश पालीवाल,** अकलतरा (म.प्र.)

■ आवरण कथा पढ़ने से साफ हो जाता है कि असली षड्यंत्रकारी विपक्ष के गिने-चुने नेता ही हैं. ज्ञानी जी सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच घुन की तरह पिसते रहे, क्योंकि लेख में कहीं भी उल्लेख नहीं है कि ज्ञानी जी ने कोई भी बयान अपने मन से दिया.

—**जगदीश कुमार ताराचंदी,** वर्धा (महाराष्ट्र)

अंधी गली में

कसौटी स्तंभ में 'निरंकुश सत्ता की ओर' (15 अप्रैल) पढ़कर अंधी गली में राजीव के बढ़ते कदम का एहसास हुआ. 59वें संविधान संशोधन विधेयक के बाद पंजाब एक सरकारी कत्लगाह बनकर रह जाएगा. इस विधेयक की आड़ में सरकार प्रेस पर भी लगाम लगाने की कोशिश करेगी.

— **नलिन मलहीपुरी,** बरौनी (बिहार)

■ सरकार जिस तरह पंजाब में नए-नए कानून बनाकर वहां के लोगों को जीने और स्वतंत्रता के उनके अधिकार से वंचित रख रही है उसे देखते यह कहना मुश्किल कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है.

—**कामरेड सरदार मनोज कुमार 'आजाद',** भागलपुर (बिहार)

■ प्रश्न यह है कि सरकार के पास असीम अधिकार होने के बावजूद वह पंजाब में शांति कायम क्यों नहीं कर सकी? दरअसल, सरकार पंजाब में इमरजेंसी लगाकर समस्या हल करने की ताक में है, लेकिन यदि इमरजेंसी रूपी तलवार भी उस रण-क्षेत्र में टूट जाए तो क्या होगा?

—**प्रदीप कुमार सिंह,** चाकघाट (म.प्र.)

■ सच तो यह है कि 59वें संविधान संशोधन की आड़ लेकर राजीव सरकार भारत में नात्सीवाद और फासीवाद की ऐसी इमारत खड़ा कर रही है, जिसका कि पतन निश्चित है.

—**प्रणय कुमार मिश्र,** जमालपुर (बिहार)

■ सरकार को पहले ही जरूरत से ज्यादा अधिकार मिले हुए हैं, फिर यह 59वां संशोधन क्यों? सरकार जब इतने अधिकार मिलने पर भी पंजाब समस्या का समाधान नहीं ढूंढ सकी तो क्या इस एक संशोधन से सारी स्थिति बदल जाएगी. वास्तव में सरकार को संकल्पशक्ति चाहिए न कि इतने अधिक अधिकार.

—**पवन कुमार कामरा,** भिवानी (हरियाणा)

ठाकरे का ठेका

'शेर की गुर्राहट' (15 अप्रैल) पढ़ा. ठाकरे साहब खुद को एक देशभक्त साबित करना चाहते हैं लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा कि सिखों का बहिष्कार सांप्रदायिकता को ही बढ़ावा देगा. इस धमकी से तो आतंकवादी शायद खुश ही होंगे क्योंकि वे तो चाहते हैं कि पंजाब से बाहर के सिख भी पंजाब आ जाएं और पंजाब के हिंदू बाहर चले जाएं.

—**रवींद्र सिंह छाबड़ा,** लुधियाना (पंजाब)

■ लेख बेहद सटीक लगा. सचमुच बाल ठाकरे द्वारा सिखों का बहिष्कार महज देशभक्ति का मुखौटा है, जिसे पहनकर वे सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं. शायद बाल ठाकरे नहीं जानते हैं कि सांप्रदायिकता फैलाने वाला ही सबसे बड़ा आतंकवादी होता है.

—**अरशद रिजवी,** पटना (बिहार)

■ आश्चर्य हुआ कि शेरदिल बाल ठाकरे चूहे के बिल से सारा तमाशा देखना चाहते हैं. पंजाब की समस्या बंबई के सिखों के बहिष्कार से समाप्त नहीं होगी. अच्छा होता कि शिवसेना समेत बाल ठाकरे अपने आत्मबल को मजबूत बनाकर प्रतिनिधिमंडल की अगुआई करते और आतंकवादियों को बहिष्कार का अल्टीमेटम देते.

—**कमल नयन अम्बष्ठ,** गया (बिहार)

■ लगता है बाल ठाकरे एक तीर से दो निशाने लगाने का दुस्साहस कर रहे हैं. अन्यथा पत्रकार वार्ता में खुला एलान, बेबुनियाद आरोपों की बौछार और बंबई के सिख समुदाय के लिए एक माह का अल्टीमेटम, लेकिन अपनी जान पर खतरा महसूस करते हुए उनकी अगुआई से इनकार करना

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हैलो कहने का नया अन्दाज़

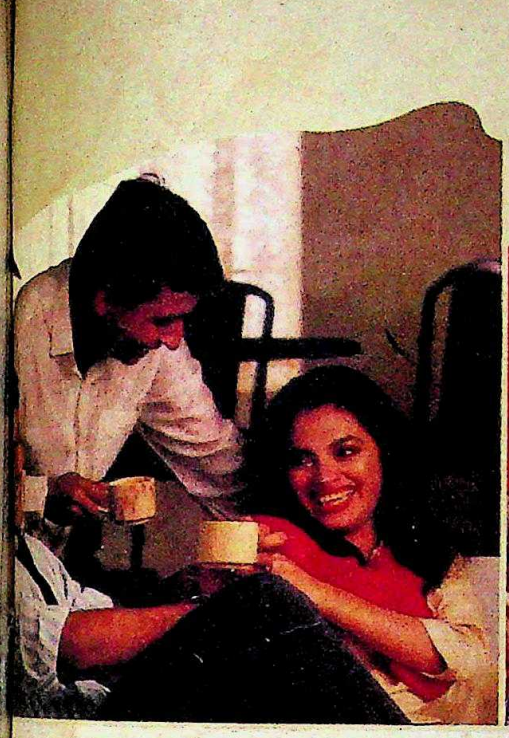

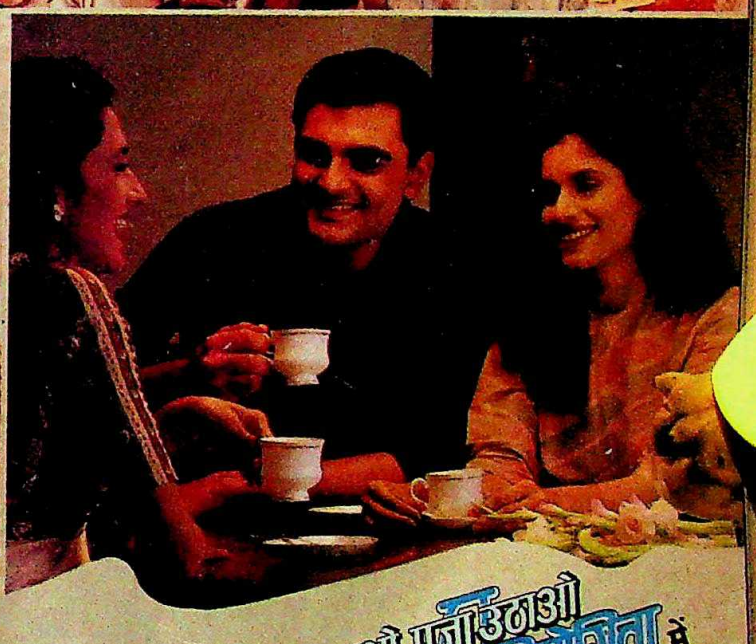

नेस्कैफ़े कॉफी

दुनिया भर की मनपसन्द कॉफ़ी

संग होने की उमंग, जगाए तरंग ऐसे लम्हों में **नस्कैफ़े**.
शत प्रतिशत शुद्ध, ताज़ा कॉफी का आनन्द लीजिए.
नैस्कैफ़े का खास स्वाद-आपके लिए खास तौर से लाए हैं
वो लोग, जिनसे बेहतर कॉफी के बारे में और कोई नहीं जानता.
जब सब संग साथ हो ऐसे लम्हों में-**नैस्कैफ़े**
ऐसा स्वाद जिस पर दुनिया करे नाज़.

संग होने की उमंग

ठंडक पाओ मज़ा उठाओ **प्रतियोगिता** में भाग लीजिए

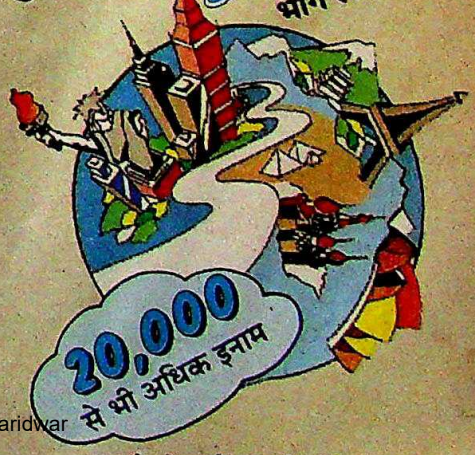

अपने डीलर से सम्पर्क कीजिए.

TSA/FSL/126/HIN

CC-0. In Public Domain. Gur... on, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Handloom Emporium is much more than this...

Sarees

Readymades–Men

Gifts

Children's Wear

Furnishings

Silks

Tailoring

Travel Goods

...ades–Women

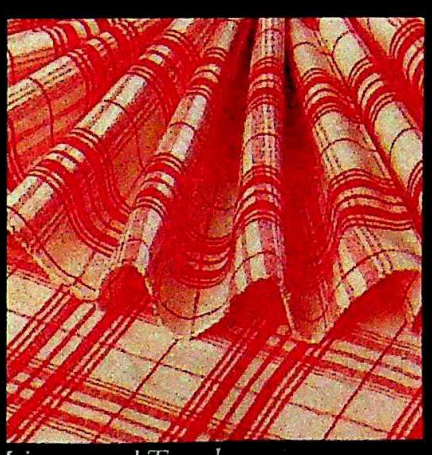

Linen and Towels

and Care...

It is Elegance. Style. And Class.

handloom® emporium

G 12 SOUTH EXTN 1 NEW DELHI 110049 PH 623208

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"कुछ नवीन, कुछ अद्‌भुत... खेतान ने फिर कमाल किया"

"इसीलिये तो मैं खेतान फैन हूँ"

– हेमा मालिनी

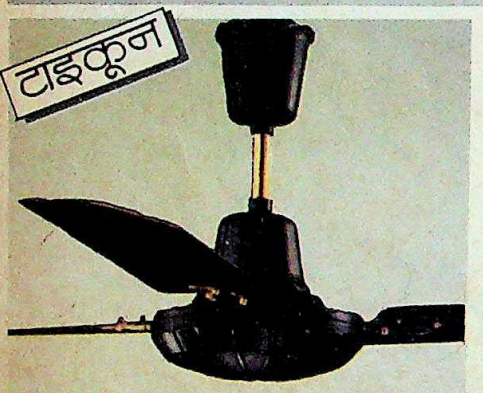

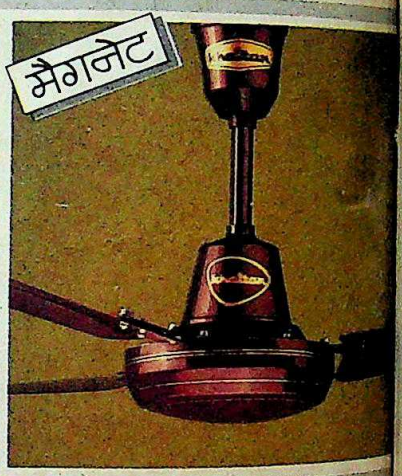

पेश हैं खेतान 3up पंखे

हर कीमत पर क्वालिटी, हर समय अनुसंधान। ये हैं खेतान की जान! खेतान अनुसंधान केन्द्र को भारत सरकार की मान्यता का गौरव प्राप्त है। इस केन्द्र द्वारा बहुत परीक्षणों के पश्चात् एक नई शृंखला के सीलिंग पंखों का निर्माण संभव। वे हैं 'खेतान' 3 up पंखे। समुचित गुण सम्पन्न नये खेतान 3 up पंखों की ३ विशिष्टतायें इस प्रकार हैं:

1up

ज्यादा हवा

नये खेतान 3 Up पंखों में अधिक शक्तिशाली मोटर–अधिक लेमिनेशन, अधिक कापर और अधिक पोल के कारण। नतीजा: काफी ज्यादा हवा–यदि 'खेतान' को देश का सबसे हवादार पंखा कहा जाये तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं।

2up

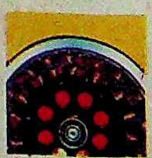

ज्यादा सक्षम... ज्यादा टिकाऊ

नये खेतान 3 Up पंखों की अनोखी कार्यकुशल मोटर। नतीजा: हर वॉट बिजली खर्च पर मिले अधिक हवा। साथ ही मोटर का तापमान कम रहने से पंखे ज्यादा टिकाऊ।

3up

विश्वास की पराकाष्ठा

नये खेतान 3 Up पंखों की उत्कृष्टता एवम् उच्च कार्यक्षमता पर हमारा असीमित विश्वास है। नतीजा: भारत में सर्वप्रथम 'खेतान' द्वारा अनोखी की 'रिप्लेसमेंट बांड' की सुविधा अर्थात् किसी भी खेतान 3 Up उत्पादकीय त्रुटि मिलने पर एक मरम्मत न कर तुरंत बदलने का वादा।

सचमुच घरेलू उपकरणों में एक नया बिस्फोट!

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

खेतान – सिर्फ नाम ही काफी है

TA 3306

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आखिर किस मानसिकता का परिचायक है.
—विजय सालोड़े, भोपाल (म.प्र.)

राष्ट्रीय अपराध

'जाने कहां गए वो दिन' (15 अप्रैल) में टीपू सुल्तान के वंशजों की तंगहाली पढ़कर बेहद दुख हुआ. भारत में धर्मार्थ ट्रस्टों का दुरुपयोग आज आम बात हो गई है. सरकार को देश के सबसे बड़े और धनवान मुस्लिम ट्रस्ट में हो रही अनियमितताओं की ओर ध्यान देना चाहिए. टीपू के वंशजों को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए.—प्रशांत कुमार सिन्हा, बेतिया (बिहार)

■ अब सन् 1799 में श्रीरंगपत्तनम में अंग्रेजों से लड़कर शहीद होने वाले 'मैसूर के शेर' टीपू सुल्तान के वंशजों की फाकाकशी का समाचार पढ़कर धैर्य टूटने लगा है. क्या हमारे नेताओं को अपने कुर्सी-युद्ध से इतनी भी फुरसत नहीं कि शहीदों के परिवार की सुध लें.
—मुकुंद दास, जबलपुर (म.प्र.)

■ जिस दौर से टीपू के वंशजों को गुजरना पड़ रहा है यह एक राष्ट्रीय अपराध है. जब टीपू के वंशज दाने-दाने के लिए तरस रहे हों तो उन्हीं की संपत्ति पर स्थापित ट्रस्ट से धार्मिक और सामाजिक कार्यों का औचित्य बेबुनियाद लगता है. टीपू वंशजों को उनकी संपत्ति वापस मिलनी ही चाहिए.
—संजय कुमार, पटना (बिहार)

■ लेख पढ़कर लगा कि नवाब हैदर अली की बेगमें खानदान की इज्जत के नाम पर अपने बच्चों के भविष्य की बलि दे देंगी. उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं पर काम नहीं करेंगी. स्कूल में फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं तो स्कूल छुड़वा देंगी. बेटियों की शादी नवाबों से ही हो. नहीं तो शायद वे शादी ही नहीं करेंगी. शायद काम न करने में ही उनके खानदान का सम्मान होगा.
—निखिल मिश्र, होशंगाबाद (म.प्र.)

धर्म या अधर्म?

'मासूम की नामालूम मौत' (15 अप्रैल) पढ़ कर दिल दहल गया. धर्म की आड़ में वासनाओं की पूर्ति, पैसे के लालच और व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण कितनी ही वारदातें और हत्याएं होती रहती हैं. ऐसे में समाज का भी दायित्व है कि ऐसे छद्मवेशधारी अपराधी तत्वों को बेनकाब करें.
—शिवपूजन तिवारी, उन्नाव (उ.प्र.)

अच्छी मिसाल

'बीते वैभव की पुनर्स्थापना' (15 अप्रैल) में आपने एक दुर्लभ जानकारी दी है. पुरातात्विक दृष्टि से इतने महत्वपूर्ण मंदिर का पुनरुद्धार करके निश्चय ही विश्व भर के पर्यटकों को आकर्षण का एक नया केंद्र उपलब्ध कराया जा सकेगा.
—बृजराज किशोर, देहरादून (उ.प्र.)

■ भारत सरकार की पहल पर अंगकोर वाट के मंदिर के पुनरुद्धार का प्रयास न केवल हमारी सहयोग की भावना की एक अच्छी मिसाल है, बल्कि प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखने का एक सुंदर प्रयास भी.
—रानो राकेश पस्टारिया, गोलापुरा हरदा (म.प्र.)

■ दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर अंगकोर वाट के बारे में ज्ञानवर्धक जानकारी मिली. कंपूचियाई सरकार ने मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए जो प्रतिष्ठाजनक जिम्मेवारी सौंपी है वह भारत के लिए गर्व की बात है.
—रमेश कुमार साहू, पानीतोला (असम)

■ लेख की प्रत्येक पंक्ति अंगकोर वाट के प्रति उत्सुकता और जिज्ञासा पैदा करती रही. अंत में यही लगा कि अंगकोर वाट की सैर कर उस मंदिर के वैभव का दर्शन किया जाए जो विश्व इतिहास की सचमुच अनुपम कृति और अनमोल धरोहर है.
—लता गुप्ता, बीना (म.प्र.)

शौर्य का सम्मान

'शौर्य की बिसरी गाथा' (15 अप्रैल) पढ़ी. 23 वर्षों के बाद स्क्वाड्रन लीडर ए.बी. देवय्या को महावीर चक्र देना उस बलिदानी वीर का सच्चा सम्मान है. देर आए दुरुस्त आए.
—उपदेश उमेश सक्सेना, रतलाम (म.प्र.)

■ स्क्वाड्रन लीडर देवय्या के बलिदान ने आज सारे भारत को गौरवान्वित किया है. अपने पुराने विमान के साथ दुश्मन के अत्याधुनिक विमान से टक्कर लेना और उसे मार गिराना उनके अदम्य साहस और देशभक्ति का ही परिचायक है.
—पवन दत्ता, रादौर (हरियाणा)

खुशगवार आंकड़े

इलाहाबाद में जनमत सर्वेक्षण 'वी.पी. सिंह का पलड़ा भारी' (15 अप्रैल) पढ़ा. यह खुशगवार लगा कि वी.पी. सिंह अभी भी आगे हैं. मर्दों में तो वी.पी. सिंह की लोकप्रियता बढ़ी ही है. दुख की बात तो यह है कि इलाहाबाद की 60 फीसदी जनता बोफोर्स के बारे में जानती तक नहीं.
—श्रवण कुमार, पाली-मारवाड़ (राज.)

भरपाई का खेल

'दक्षिण पर तूफानी धावा' (15 अप्रैल) पढ़ा. उत्तर भारत में अपनी घटती लोकप्रियता की भरपाई राजीव गांधी दक्षिण में अपने पिट्ठुओं की घुसपैठ कराके करना चाहते हैं. दक्षिणी राज्यों में जनता द्वारा चुनी गई विपक्षी राज्य सरकारों पर बेजा हमले करके राजीव देश में अस्थिरता और अराजकता को ही बढ़ावा दे रहे हैं.
—जया 'नगिस', भोपाल (म.प्र.)

ठीक नहीं किया

'लॉन टेनिस: घाटा ही घाटा' (15 अप्रैल) पढ़ा. राजीव गांधी को खेल भावना और अपने वायदे के अनुसार भारत को इज़रायल से खेलने की अनुमति देनी चाहिए थी. अमृतराज बंधुओं को चाहिए कि जीशान अली और फरेरा जैसे उदीयमान खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर उन्हें आगे लाएं जिससे भारत लॉन टेनिस में अपना स्थान बना सके.
—अरविंद कुमार श्रीवास्तव, बस्ती (उ.प्र.)

■ राजनैतिक कारणों से भारतीय लॉन टेनिस टीम को इज़रायल से खेलने की मंजूरी न देकर भारत सरकार ने ठीक नहीं किया. बहिष्कार के लिए अब भारत को 3 वर्ष के लिए निलंबन एवं 10 हजार डॉलर दंड स्वरूप भरने पड़ेंगे.
—भरत जैन, सागर (म.प्र.)

केंद्र ही जिम्मेदार

'सियासी खेल के शिकार' (15 अप्रैल) पढ़कर यही धारणा बनती है कि पंजाब की दयनीय स्थिति की जिम्मेदार केंद्र सरकार ही है. ऑपरेशन ब्लूस्टार के समय स्वर्ण-मंदिर में बंदी बनाए गए लोगों के बारे में जांच करवाकर बेकसूर लोगों की रिहाई का कोई भी प्रबंध नहीं किया गया. संभव है उस व्यक्ति के परिवार वाले केंद्र सरकार से बदला लेने के लिए प्रयत्न करते हों.
—सुधीर गुप्ता, इलाहाबाद (उ.प्र.)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तहकीकात नहीं तमाशा

जांच या इस्तगासा एजेंसियों को जितने अधिकार भारत में प्राप्त हैं उतने शायद ही किसी और देश में होंगे. और ऐसी जितनी तरह की एजेंसियां भारत में हैं उतनी शायद ही किसी और देश में होंगी—सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय, राजस्व गुप्तचर निदेशालय, आर्थिक खुफिया ब्यूरो आदि-आदि. और इन तमाम एजेंसियों और उनके तमाम अधिकारों का जिस तरह मजाक हमारी सरकार बनाती है, वैसा शायद ही किसी दूसरे देश में होता होगा. स्वीडिश बोफोर्स तोपों और जर्मन पनडुब्बियों से संबंधित विवादों के संदर्भ में यह तथ्य साफ उजागर हो गया है.

तभी शायद इन खोजबीन एजेंसियों को मजाक में लीपापोती एजेंसियां कहा जाने लगा है. टैक्स छापे जिस तरह सोच-समझकर और किसी इरादे से प्रेरित होकर मारे जाते हैं, सीबीआई जिस तरह झूठे मामले दर्ज करती है, फिर हाल के दिनों में जो कुछ तमाशा हुआ है उससे तो यह मजाक मजाक नहीं, सच लगने लगा है. वास्तव में जांच आयोग और संसदीय समितियां राजनीति के शर्मनाक खेलों का जैसे साधन ही बन गई हैं. और जो प्रधानमंत्री कभी जर्जर होती जा रही संस्थाओं में जान फूंकने की बातें किया करता था, आज इन एजेंसियों की बची-खुची विश्वसनीयता को भी मटियामेट करने के प्रयासों का बड़े संतोष भाव से संचालन करने लगा है.

रेखाचित्र: अजीत नाइनन

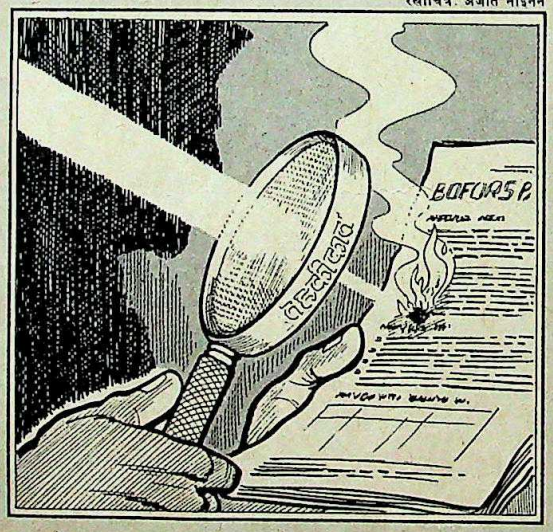

अमेरिका के प्रसिद्ध वाटरगेट कांड में पत्रकारों ने एक मुकाम तक तो खोजबीन की. उसके बाद का काम सीनेट कमेटी, विशेष अभियोक्ता और अदालत ने किया. दुर्भाग्य से भारत में मामला उलटा है. यहां प्रायः हर घोटाले का रहस्योद्घाटन प्रेस करता है और सबूत जुटाने के लिए हर संभव कोशिश करता है, बाहरी स्रोतों तक की मदद लेता है. दूसरी ओर जांच समितियां हैं जिन पर कानूनी जिम्मेदारी तो है भ्रष्टाचार और कुकर्म की तहकीकात की, लेकिन जिनका इस्तेमाल सत्ता में बैठे लोग इस तरह से करते हैं कि सच उजागर न होने पाए.

इसकी मिसाल भी देखिए. पश्चिम जर्मनी की राजधानी बॉन में एक जर्मन अधिकारी भारतीय राजदूत को बताता है कि पनडुब्बी कंपनी एचडीडब्ल्यू भारत को बेची गई पनडुब्बियों पर, एक भारतीय दलाल के साथ करार के तहत उसे 7 फीसदी दलाली दे रही है. इस रहस्योद्घाटन के बाद तमाम तरह की जांच एजेंसियां साल भर खोजबीन करती हैं और अंततः रक्षामंत्री संसद में बयान देते हैं कि कोई दलाली नहीं दी गई.

उधर बोफोर्स घोटाले की जांच कर रही संसदीय समिति की रिपोर्ट भी लगभग इसी दौरान तैयार होती है जिसमें सरकार को पाक-साफ बताने की कोशिश की गई है. लेकिन तभी एक अखबार के जरिये कुछ और तथ्य प्रकाश में आते हैं जिनसे साफ हो जाता है कि मामले की तह तक न तो संसदीय समिति पहुंच पाई है और न ही उसकी सहायता करने वाली दूसरी सरकारी एजेंसियां.

सरकारी जांच एजेंसियां महीनों की 'गोताखोरी' के बाद अक्सर खाली हाथ ही निकलती दिखती हैं. इसका ताजा उदाहरण भर ही हैं उपरोक्त दोनों मामले. फेयरफैक्स मामले को जिस फर्जी चिट्ठी ने बिलकुल नया मोड़ दे दिया था न तो उसके बारे में कुछ कहा गया और न ही स्विट्जरलैंड में अजिताभ बच्चन के फ्लैट खरीदने के बारे में. रिलायंस कंपनी को कुछ चीजों के आयात के लिए पिछली तारीख से अधिकारपत्र जारी करने के आरोपों की सीबीआई जांच के बाद कुछ बैंक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तो हुई लेकिन उस कंपनी को छुआ तक नहीं गया.

कई घोटाले सामने आए और चुपचाप दबा दिए गए. बोफोर्स विवाद की धूल उड़ते ही पिछले वर्ष हथियारों के 17 व्यापारियों के यहां छापे मारे गए लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ. सरकारी गोपनीयता कानून के उल्लंघन के आरोप में सेना के एक जनरल के घर पर छापा मारा गया और फिर आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई. इंडियन एक्सप्रेस के सलाहकार एस. गुरुमूर्ति के खिलाफ कार्रवाई एक साल पहले शुरू की गई थी लेकिन सीबीआई ने आज तक कोई आरोपपत्र नहीं दर्ज किया है. राजिंदर सेठिया के मामले से जुड़े प्रश्न आज भी जवाब मांग रहे हैं. तो उधर रामस्वरूप प्रसंग से कई बड़े नामों का (जिनका वास्तव में हकीकत से खास ताल्लुक नहीं) जुड़ा होना अलग सवाल खड़े करता है.

संभव है सभी मामलों को सोच-समझकर गलत दिशा में मोड़ने की कोशिश न की जाती रही हो. हो सकता है कि घालमेल अक्सर जांच एजेंसियों की अपनी कुव्यवस्था के कारण हो जाता हो जिनमें प्रायः एक नहीं, कई-कई सर्वेसर्वा होते हैं. लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सत्ता में बैठे लोग इन एजेंसियों का बेहतर इस्तेमाल करने के बजाय इनकी मदद से लीपापोती की कोशिशें ही करते रहे हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि वे किसी को मूर्ख बनाने में कामयाब हो गए हों.

सवाल बहुत सरल है. जांच एजेंसियां अगर तहकीकात नहीं करतीं और इस्तगासा एजेंसियां मुकदमा नहीं दर्ज करतीं तो कोई क्या करे? जवाब शायद यही है कि इन एजेंसियों को जितना संभव हो कार्यपालिका के दबाव से मुक्त किया जाना चाहिए. एक रास्ता यह हो सकता है कि उन्हें नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की तरह ही संवैधानिक स्वतंत्रता दी जाए. या फिर दूसरे देशों की व्यवस्था से सबक लिया जाए. अगर इन परिवर्तनों के लिए जनमत तैयार किया जाए और विपक्षी पार्टियां इसे अपना राजनैतिक मुद्दा बनाएं तो सरकार को इस दिशा में कार्रवाई करने पर मजबूर किया जा सकता है, वरना इन एजेंसियों के खुल्लमखुल्ला 'इस्तेमाल' पर रोक लगना मुश्किल ही है.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विश्व-प्रसिद्ध शृंखला

पुस्तक महल की 30 पुस्तकों का एक अनूठा प्रोजेक्ट

मूल्य: 12/- प्रत्येक
डाकखर्च: 3/- प्रत्येक
एक साथ चार पुस्तकें मंगाने पर **डाकखर्च माफ**

- प्रामाणिक पाठ्य-सामग्री
- प्रत्येक पुस्तक सैकड़ों दुर्लभ चित्रों से सुसज्जित
- सरस कथा शैली
- फोटोटाइप सैट
- बढ़िया कागज पर ऑफसैट छपाई
- बहरंगी आवरण
- वाजिब दाम

इस शृंखला का मूल उद्देश्य एक औसत पाठक को अंतर्राष्ट्रीय जगत से जोड़कर उसकी चेतना को प्रबुद्ध करना है।

कुल मिलाकर प्रत्येक पुस्तक अपने क्षेत्र से संबंधित सभी उल्लेखनीय पक्षों को पूर्ण रूप से उजागर करने वाला एक सचित्र **'मिनि एनसाइक्लोपीडिया'** है।

उदाहरणार्थ 'रोमांचक कारनामे' में सरकंडे की नाव में की गई 13,000 मील की समुद्री यात्रा जैसी अनेक सच्ची कथाएं हैं तो 'खोजें' में मिट्टी के तेल, पेनिसीलीन आदि खोजों के पीछे छिपे प्रयासों का रोचक विवरण है। 'अनसुलझे रहस्य' में बरमूदा ट्राइएंगल से लेकर भूत-प्रेतों तथा रक्त मिलाकर शराब पीने वाली जातियों तक के रहस्य हैं तो 'खेल और खिलाड़ी' व 'वैज्ञानिक' क्रमशः जीवनी प्रधान पुस्तकें हैं। 'विनाश-लीलाएं' में प्रकृति के प्रलयंकारी रूप का चित्रण है तो 'दुर्घटनाएं' में मानवीय भूलों से हुई ममांतक तबाहियों का लेखा-जोखा है। 'गुप्तचर संस्थाएं' तथा 'जासूस' में मकड़े के जालों सी फैली जासूसी संस्थाओं तथा उनमें कार्यरत जासूसों की रोमांचकारी गतिविधियां हैं तो 'प्रेरक-प्रसंग' किसी भी जहाज की तरह भटके हुए मन के लिए प्रकाश-स्तंभ है।

अब तक प्रकाशित पुस्तकें:

विश्व-प्रसिद्ध.... 1. खोजें 2. अनसुलझे रहस्य 3. रोमांचक कारनामे 4. युद्ध 5. 101 व्यक्तित्व 6. धर्म, मत एवं सम्प्रदाय 7. खेल एवं खिलाड़ी 8. रिकॉर्ड्स (भाग-I) 9. रिकार्ड्स (भाग-II) 10. वैज्ञानिक 11. विनाश-लीलाएं 12. दुर्घटनाएं 13. गुप्तचर संस्थाएं 14. जासूस 15. प्रेरक-प्रसंग।

आमंत्रण:—

प्रोजक्ट में योगदान के लिए विद्वान लेखक तथा अनुवादक संपर्क साधें।

जून, 1988 तक प्रकाश्य:

- विश्व-प्रसिद्ध जासूसी-कांड
- विश्व-प्रसिद्ध सभ्यताएं

तैयारी में/प्रैस में:

- चिकित्सा-पद्धतियां
- स्कैण्डल
- बैंक-डकैतियां
- राजनैतिक हत्याएं
- खोजी-यात्राएं
- क्रूर हत्यारे
- खजाने।

VAN/PM/24

अपने निकट के बुकस्टाल एवं रेलवे तथा बस अड्डों पर स्थित बुकस्टालों पर मांग करें अन्यथा वी.पी.पी. द्वारा मंगाने का पता

पुस्तक महल, खारी बावली, दिल्ली-110006

शो रूम : 10-B नेताजी सुभाष मार्ग, दरिया गंज, नई दिल्ली-2.

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अफसरों की मुसीबत

● बोफोर्स विवाद ने जहां प्रधानमंत्री राजीव गांधी की नाक में दम कर रखा है, वहीं चेकोस्लोवाकियाई सीजेड-75 पिस्तौले जनमोर्चा के नेता अरुण नेहरू के जी का जंजाल बन गई हैं. दुर्भाग्य से कुछ ईमानदार अफसर इस दोतरफा गोलाबारी में फस गए हैं. उनमें से एक

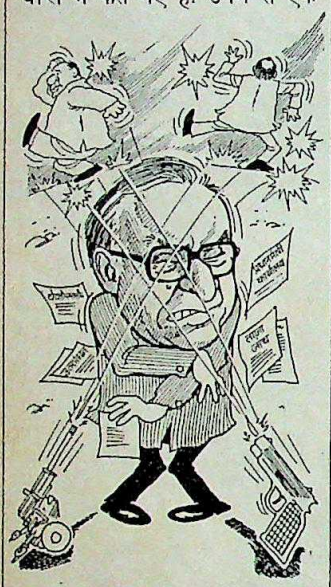

हैं गृह सचिव सी.जी. सोमय्या.

चेक पिस्तौलों पर विवाद इस साल के शुरू में ही शुरू हुआ जब सरकार ने पुलिस के लिए मंगवाई गई 11,500 पिस्तौलों की एक खेप अचानक ही लौटा दी. इसके लिए भुगतान की गई 3.17 करोड़ रुपए की रकम भी उसने इस आधार पर लौटा ली कि ये हथियार परीक्षणों में घटिया पाए जाने के बावजूद खरीद लिए गए थे. उधर सीबीआई ने नेहरू के खिलाफ कार्यविधि के विभिन्न उल्लंघनों के आरोपों में मामला दर्ज किया है.

पर अब सीबीआई ने उन अधिकारियों की सूची में सोमय्या का नाम भी जोड़ लिया है जिनसे पूछताछ की जानी है. पिछले साल प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोमय्या को एक चिट्ठी में पूछा था कि पिस्तौलों का प्रथम मूल्यांकन किन लोगों ने किया था. गृह सचिव ने अपने विशिष्ट अंदाज में जवाब दिया था कि यह काम केंद्रीय पुलिस संगठनों के तीन प्रमुखों और मंत्रालय के एक अतिरिक्त सचिव ने किया है. उनका यह भी कहना था कि "मामला खत्म समझा जाना चाहिए." लेकिन अब जबकि मामला दुबारा खुला है तो लगता है कि सोमय्या सरीखे लोगों पर भी कीचड़ उछलेगा.

प्रतापी कॉलोनी

● दक्षिण दिल्ली की सोम विहार कॉलोनी इन दिनों रक्षा मंत्रालय की चर्चा का केंद्र बनी है. यह बस्ती विशेष तौर पर सैनिक अफसरों के लिए बसाई गई थी. साउथ ब्लॉक के अधिकारी तो इस पर उंगलियां भी उठाने लगे हैं. उन्हें अंदेशा है कि यह कॉलोनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा सिद्ध हो सकती है. कुमार नारायण और लारकिंस बधुओं के मामलों के बाद सैनिक अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि वे विदेशी राजनयिकों के साथ मेलमिलाप कम कर दें. अफसरों के घरों को विदेशी दूतावासों को किराये पर देने से संबधित नियमों को भी कड़ा कर दिया गया था.

लेकिन सोम विहार में इन नियमों को तिलांजलि दे दी गई लगती है. हालांकि सैकड़ों सैनिक अधिकारी और उनके परिवार अभी वहां रहते हैं पर बहुत से अफसरों ने अपने फ्लैट विदेशी दूतावासों को

सभी कार्टून: अजीत नाइनन

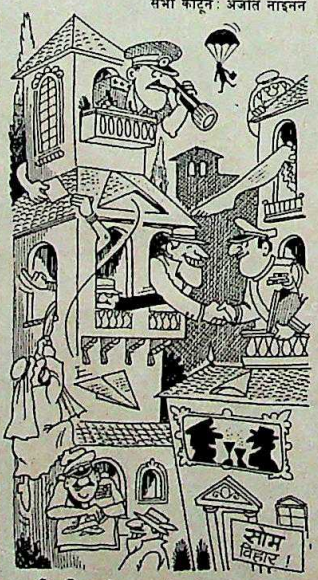

भारी किराये पर दे दिए हैं. इसके अलावा उन्होंने मुख्तारनामे के आधार पर भी अपने फ्लैट बेचने शुरू कर दिए हैं. रक्षा मंत्रालय को इस पर भी एतराज है क्योंकि सोम विहार कोऑपरेटिव सोसायटी का बसाया हुआ है और मुख्तारनामे के आधार पर खरीद-फरोख्त यहां नियम के विरुद्ध है.

बर्र के छत्ते का खौफ

● ज्ञानी जैल सिंह को दुबारा राष्ट्रपति चुनाव लड़ाने और इंका के अधिकृत उम्मीदवार के मुकाबले खड़ा होने के लिए 30 से 40 करोड़ रुपए के बीच की गई पेशकश का ज्यों ही रहस्योद्घाटन किया था खुद जैल सिंह ने, तो कांग्रेसी हलके में खुशी की लहर दौड़ गई थी. सर-

कार ने आनन-फानन में इन आरोपों की जांच कराने का वायदा कर लिया था. लेकिन आज पता नहीं उस वायदे का क्या हुआ? जब ये आरोप खुद पूर्व राष्ट्रपति ने एक पत्रिका में लगाए थे तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संसद में उठकर कहा था कि गृहमंत्री बूटा सिंह को इनकी जांच करने और दोषी की शिनाख्त करने के लिए कहा गया है.

पर मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार यह जांच बीच में ही चुपचाप छोड़ दी गई है क्योंकि इसके दोधारी राजनैतिक तलवार बन जाने का अंदेशा था. प्रधानमंत्री और उनके सलाहकारों का मानना है कि राजीव उस पुराने राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री विवाद में विजयी होकर उभरे हैं. वजह यह कि जैल सिंह ने गाहे-बगाहे जो परस्पर विरोधी बयान जारी किए उससे उनकी विश्वसनीयता जाती रही. प्रधानमंत्री खेमे का यह भी मानना है कि इस मौके पर जांच कराने से मामला उलट भी सकता है. जांच में अगर जैल सिंह के कुछ आरोप भी सही पाए गए तो? इससे पूर्व राष्ट्रपति की विश्वसनीयता ही बहाल होगी और इंका में तूफान उठेगा सो अलग. इसलिए बेहतर है बर्र के छत्ते में हाथ ही न डाला जाए.

रिश्तों के बूते

● विदेश मंत्रालय में पिछले दिनों एक वरिष्ठ विदेश सेवा अधिकारी चर्चा में रहे. उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ अपने ठोस संबंधों का लाभ मिला था और वे लगातार आठ साल तक एक ही पद पर विराजमान रहे. अमूमन मंत्रालय में कोई अधिकारी एक पद पर तीन साल ही रहता है. पर ये अफसर महोदय 1980 से पश्चिमी यूरोप डेस्क पर संयुक्त सचिव बने रहे. मंत्रालय की विपरीत सलाह के बावजूद उनकी कार्यावधि प्रधानमंत्री कार्यालय के आदेश से निरंतर बढ़ाई जाती रही.

मामला उस समय चरम पर पहुंच गया जब मंत्रालय के उच्चाधिकारियों को पता लगा कि संयुक्त सचिव की पत्नी ऐसे कारोबार में लगी हैं जिसके हित उनके पति के अधीन विभाग से जुड़े हुए हैं. शुरू में कुछ वरिष्ठ राजनयिकों के विरोध के बावजूद मंत्रालय के कानों पर जूं

नहीं रेंगी आखिर उनमें से कुछ ने प्रधानमंत्री कार्यालय को चेतावनी दे दी कि अगर संयुक्त सचिव को पांच दिन के भीतर ही नहीं हटाया गया तो कुछ बड़े अफसर इस्तीफा दे देंगे. ऐसी नौबत आती इससे पहले ही उक्त अधिकारी का तबादला करके उन्हें नेशनल डिफेंस कॉलिज भेज दिया गया.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

माईकलएंजलो की चित्रकारी। बेलटेक ने क्या खूब निखारी।

माईकलएंजलो को यह खूबसूरत पेंटिंग बनाते वक्त गुमान भी नहीं रहा होगा कि, आज टेलीविज़न की आधुनिकतम खूबियों के ज़रिये उसमें इतनी जान डाली जा सकती है। बेलटेक के इस कमाल पर माईकलएंजलो भी रह जाता हैरान!

बेलटेक पेश करते हैं बी टी के-777 अतिआधुनिक और नयी-नयी खूबियों के साथ—

- साफ तस्वीर
- देखने से आँखों पर बिल्कुल जोर नहीं
- ऑन स्क्रीन डिस्प्ले चैनल, वॉल्यूम, कलर और चमक (ब्राइटनैस)
- ऑफ टाइमर
- ऑटो सर्च ट्यूनिंग
- बर्स्ट क्लीनिंग सर्किट
- फुल फंक्शन रिमोट कंट्रोल

BELTEK

तस्वीर जो खुद कहे कहानी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मध्य प्रदेश का कुन्डम गांव! शाम ढले, जब पंछी अपने नीड़ की ओर लौटते हैं, सुशीलाबाई भी अपने कर्मवीर पति की वापसी की राह देखती हुई अपनी नन्हीं-मुन्नी रजनी को बहलाती है। उसका नन्हा बेटा बलराम भी गौओं के साथ खेलता-कूदता लौटने वाला है। नन्हीं रजनी की किलकारियां उसे उस वक्त की याद दिलाती हैं... आज से ८ साल पहले जब उनका नया-नया ब्याह हुआ था और उन्होंने परिवार कल्याण के लिए नियोजन का संकल्प लिया था, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित और खुशहाल रहे। आई टी सी ने उन्हें राह दिखायी...

कुन्डम की सुशीलाबाई।
नये ब्याह के हुलास के साथ इन्हें चिन्ता थी कि इनकी नियति छः बच्चों के बोझ से थकी-टूटी इनकी माँ जैसी न हो।

तभी आई टी सी के माध्यम से इनके पति ने परिवार नियोजन साधनों को अपनाया।

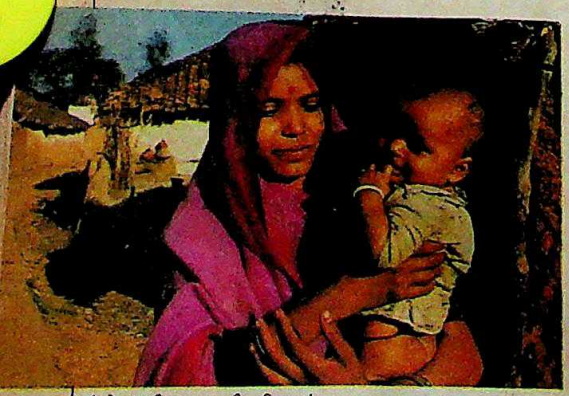

'छोटा परिवार, सुखी परिवार' की जागरूकता

सन् १९६८ से आई टी सी भारत सरकार द्वारा सुनिश्चित परिवार कल्याण कार्यक्रम में शामिल हुई और विस्तृत वितरण व्यवस्था एवं मार्केटिंग तजुर्बों के माध्यम से मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश... अब दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश तक में निरोध के साधनों का प्रचार-प्रसार कर रही है।

भारत में निरोध-साधनों की सबसे बड़ी वितरक के रूप में आई टी सी ने खासतौर पर यह कोशिश की है कि देश के लोगों में छोटे परिवार के फ़ायदों के प्रति जागरूकता बढ़े।

सन् १९८९-९० तक यह कंपनी जन शक्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम और निरोध-साधनों के प्रचार योजना पर करीब १ करोड़ से भी ज्यादा रुपए खर्च करेगी।

सरकार के फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेन्ट के सहयोग से आई टी सी इतने सारे इलाकों में कार्यरत है, जहां भारत की आधी आबादी बसी है। कंपनी ने उन रूढ़िवादी अंधविश्वासों के उन्मूलन की भी चेष्टा की है, जिसने देश की अधिकांश आबादी को मोहग्रस्त कर रखा है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation

मनुष्य को आत्मसम्मान और गरिमामय जीवन देने के लक्ष्य में आई टी सी के प्रयास :

ग्रामीण उद्योग : सालों के शोध और विकास के दम पर आई टी सी ने कई-कई किस्मों के तैल-बीजों के उत्पादन और विकास का भी सूत्रपात किया है, जिससे आयात की मात्रा कम होगी और हजारों-हजार किसानों के फलने-फूलने में मदद मिलेगी ।

भारतीय शास्त्रीय संगीत : कलकत्ते के संगीत रिसर्च अकादमी में परम्परा और तकनीक के गठबन्धन द्वारा आई टी सी ने गुरु-शिष्य परम्परा को जीवित रखा है और देश भर में नयी-नयी संगीत-प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दिया है ।

कुटीर-उद्योग : शाहजहांपुर में आई टी सी ने त्रिवेणी हैंडलूम्स के ज़रिए कालीन-बुनाई उद्योग को पुनर्जीवित किया ताकि २५०० से भी ज्यादा परिवार बेहतर कमा सकें, बेहतर जीवन जी सकें । कालीन निर्यात द्वारा आई टी सी विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर रही है ।

नई दिशाएँ, नई आशाएँ

Contract ITC 57 88 HIN

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्यासी तस्वीर

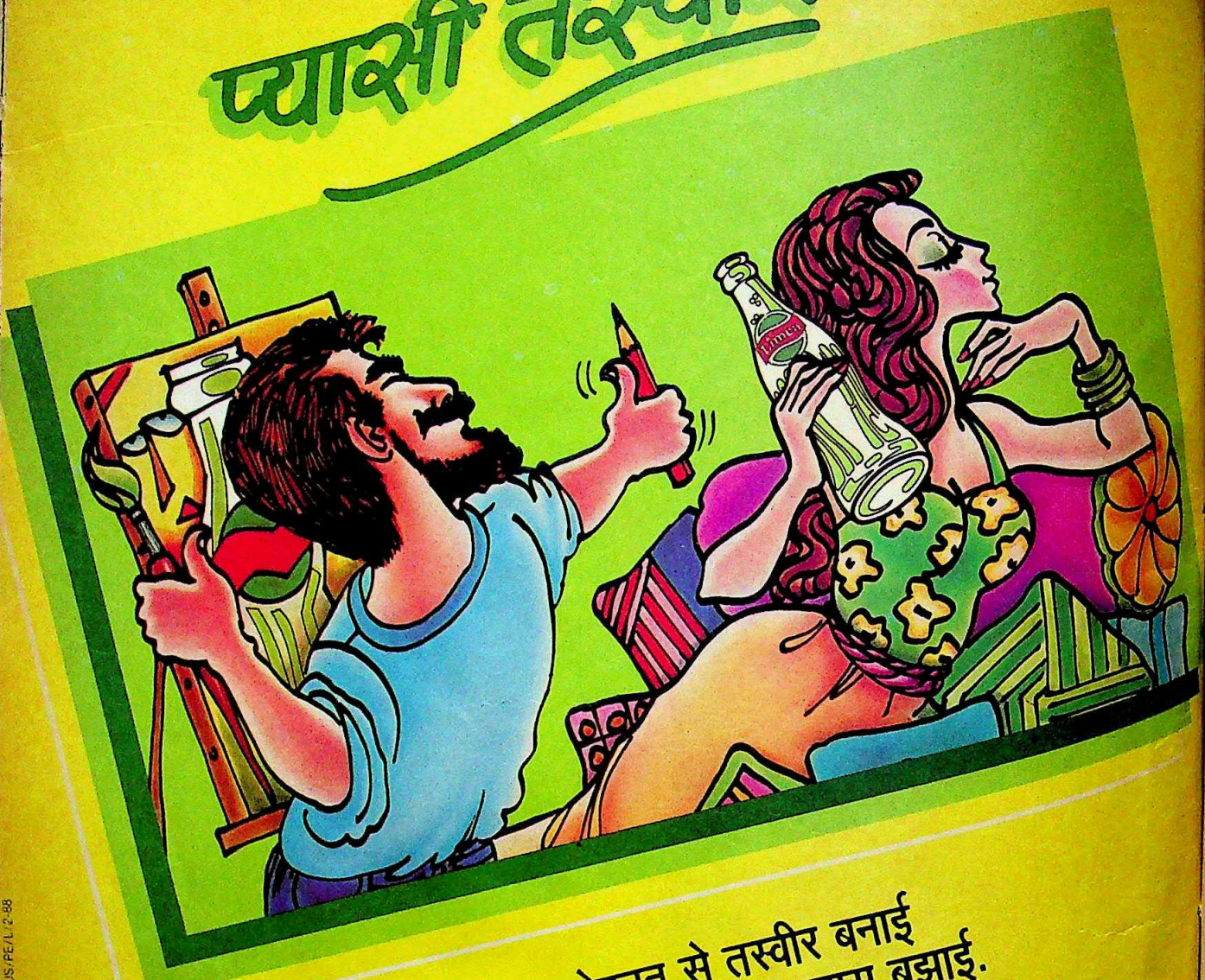

मेहनत से तस्वीर बनाई लिम्का पी कर प्यास बुझाई.

जब आप किसी 'शाहकार' की रचना करते-करते या फिर उस शाहकार के लिए 'मॉडल' करते-करते थक कर प्यास से बेहाल हो जायें तब आयसोटॉनिक साल्ट वाले किटाणुरहित लिम्का की बोतल उठायें और अपनी प्यास बुझायें.

Limca
नींबू जल-सा मज़ेदार पेय
ठंडा बर्फीला पिएं-पिलाएं

RADEUS/PE/L/2-98

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

• यदि भिंडरांवाले के परिवार को ही पंजाब संभालना है तो फिर ऑपरेशन ब्लूस्टार की क्या जरूरत थी?
■ **अरुणा आसफ अली,** *पंजाब केसरी*

• मैं किसी की पूंछ पकड़कर राजनीति में नहीं आया हूं.
■ **ओमप्रकाश चौटाला** (देवीलाल के पुत्र), *दिनमान*

• मैं आज भी पहले की ही तरह दाल-रोटी खाता हूं और सादा जीवन बिताने का कायल हूं.
■ **भजनलाल,** *संडे*

• मैं संभवत: अति लोकतंत्रवादी हूं...यदि मैंने असंतोष को शुरुआत में ही कुचल दिया होता तो आज ऐसी स्थिति नहीं होती.
■ **रामकृष्ण हेगड़े,** *राजस्थान पत्रिका*

• मैंने एक सबक जरूर सीखा है कि भविष्य में किसी भी भाजपा नेता पर चाहे वह कितना विद्वान, सज्जन और बलशाली क्यों न हो, कभी विश्वास नहीं करूंगा.
■ **अर्जुन सिंह,** *नई दुनिया*

• सोनिया बहुत ही चालाक औरत है. उसे अपने हितों का पूरा ख्याल रहता है.
■ **विजयलक्ष्मी पंडित,** *इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया*

• हमें देखे को अनदेखा करना है. हम देखेंगे कि हमें न दिखाई दे. हम देखें कि दूसरों को भी न दिखाई दे. हमें वह देखना है जो नजर नहीं आता...देखना यह है कि कहीं वह दिख न जाए.
■ **शरद जोशी** (व्यंग्यलेखक), *नवभारत टाइम्स*

• नए फिल्मकारों में अधिकांश को हिंदी आती ही नहीं और वे हिंदी फिल्मों के निर्देशक बने बैठे हैं.
■ **लक्ष्मीकांत** (संगीतकार), *रविवार*

• मैं नहीं मानती कि श्रीदेवी से मेरा कोई मुकाबला है...बॉक्स आफिस वाली फिल्मों में अब मेरी दिलचस्पी नहीं रही.
■ **रेखा,** *फिल्मफेयर*

• स्पर्धा की बात तो छोड़ो, मेरी तरह कोई 15 साल तक यहां टिककर बताए तो जानूं.
■ **मौसमी चटर्जी,** *माधुरी*

• हुजूर, अगर फिल्मों में काम नहीं करूंगा तो घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाएगा. एक सांसद के रूप में मुझे महज 2,000 रुपए माहवार मिलते हैं.
■ **सुनील दत्त,** रविवार्ता *(नवभारत टाइम्स)*

• सुविधाओं (महिला क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए) का नाम न ही लीजिए तो ज्यादा अच्छा है. बस हम ही जानते हैं कि हम कैसे खेल रहे हैं.
■ **शर्मिला चक्रवर्ती,** *हिंदुस्तान*

भरिए

यह कूपन और आपनी चहेती आवाज़ सुनिए: बच्चे की खिलखिलाहट

हंसी-खुशी और मौज-मस्ती बच्चों के लिए उतनी ही ज़रुरी हैं जितने ज़रुरी हैं खाना-पीना और हवा. और डिस्नी टुडे लेकर आया है यही मस्ती... यही मज़े.
बस तो फिर यह कूपन भर दीजिए और हर एक को खुश कर दीजिए.

आकर्षक छूट का लाभ उठाईये.

कूपन निम्नलिखित पते पर भेजें:
लिविंग मीडिया इंडिया (प्रा.) लि.
सबस्क्रिपशन डिपार्टमेंट
थॉमसन प्रेस बिल्डिंग
पो.बॉ. न० 69, दिल्ली-मथुरा रोड
फ़रीदाबाद - 121 007 (फ़रीदाबाद)

मुझे अपने बच्चे के लिए सबस्क्रिपशन चाहिए. यह रहा मेरा सालाना सबस्क्रिपशन ☐ हिंदी रु. 78/- ☐ अंग्रेजी रु. 96/- प्रति के लिए. मैं भुगतान चैक/मनी आर्डर/डिमांड ड्राफ्ट नं. _____ द्वारा कर रहा हूं.
कृपया प्रति निम्नलिखित नाम व पते पर भेजें:
नाम _____
उम्र _____ लिंग _____
डाक-पता _____
_____
_____
विद्यालय : _____
माता-पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर _____
कृपया भुगतान लिविंग मीडिया इंडिया (प्रा०) लि० के नाम पर बनाएं.

Walt Disney
डिस्नी टुडे
अब उपलब्ध हर पखवाड़े हिन्दी और अंग्रेज़ी में

© 1987 THE WALT DISNEY CO., USA.

MILESTONES/DT/114 Hin a

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'पुरस्कार' का पुरस्कार

■ इन दिनों टीवी पर दिखाए जाने वाले धारावाहिक 'पुरस्कार' का एक लक्ष्य है बच्चों को यह प्रेरणा देना कि वे साहसी बनें और मुसीबत आने पर अपने होशोहवास कायम रखते हुए उसका मुकाबला

सभी कार्टून: अनिल शर्मा

करें. इस धारावाहिक का प्रसारण करते समय दूरदर्शन अधिकारियों ने यह कल्पना भी नहीं की होगी कि किसी बच्चे पर इसका असर हाथोहाथ पड़ जाएगा.

पिछले पखवाड़े एक रविवार की सुबह मेरठ के एक मुहल्ले में एक परिवार यह कार्यक्रम देख रहा था कि तीन बदमाश डकैती के इरादे से बाहर आ जमे. अभी वे अंदर घुसने की तरकीब सोच ही रहे थे कि एक पड़ोसी वहां आ पहुंचा जो उस परिवार के लोगों को अपनी कार में किसी शादी में ले जाने के लिए आया था. ठेठ फिल्मी अंदाज में बदमाशों ने उसे धर दबोचा और पिस्तौल दिखाकर उससे दरवाजा खुलवाने को कहा. ज्यों ही दरवाजा खोला गया, तीनों बदमाश अंदर घुस गए और पिस्तौलें दिखाते हुए घर के लोगों से अलमारियों की चाबियां मांगने लगे. इसी बीच घर की 19 वर्षीया लड़की रीटा, जो दरवाजे के पास खड़ी थी, बाहर निकली और बालकनी से 15 फुट नीचे सड़क पर कूद गई. उसके शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने घर को घेर लिया. अब बदमाशों के सामने भाग निकलने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था. लेकिन अंततः लोगों ने दो को पकड़कर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया.

ठेकेदार का ठेंगा

■ इक्कीसवीं सदी की ओर कूच करने का एक लाभ यह हो रहा है कि जिंदगी का हर क्षेत्र 'व्यवस्थित' और 'सुनियोजित' होता जा रहा है. इसका प्रमाण पिछले दिनों कई राज्यों में देखने को मिला जहां से आने वाली खबरों के अनुसार इस साल स्कूली परीक्षाओं में नकल का आयोजन इक्का-दुक्का स्तर पर या छोटी-मोटी पर्चियों के माध्यम से नहीं, बल्कि ठेके पर किया गया.

लेकिन जैसा कि ठेकेदारी प्रथा में अक्सर हुआ करता है, कुछ इलाकों में ठेके विवादग्रस्त हो गए और एक मामले में तो बात जिला कलेक्टर की अदालत तक जा पहुंची. खबरों के अनुसार रायपुर के एक निकटवर्ती गांव में स्कूल के मुख्याध्यापक और कुछ अभिभावकों के बीच यह तय हुआ कि प्रति छात्र एक हजार रुपए दिए जाने पर छात्रों को परीक्षाओं के दौरान खुलकर नकल करने की छूट दे दी जाएगी. 'ठेके' पर सहमति की मुहर लगाने के लिए मुख्याध्यापक को आधी रकम का पेशगी भुगतान भी कर दिया गया. मगर किस्मत की ऐसी मार पड़ी कि शिक्षा विभाग की विशेष मुस्तैदी के कारण नकल अभियान ठप हो गया. जब अभिभावकों ने अपने पैसे वापस मांगे तो मुख्याध्यापक ने ठेंगा दिखा दिया. इस 'धोखाधड़ी'

की शिकायत लेकर अभिभावकों के संगठन ने जिला कलेक्टर के कार्यालय में फरियाद कर दी. अंतिम समाचार मिलने तक कलेक्टर महोदय मामले पर बारीकी से विचार कर रहे थे.

बेचारे शवयात्री

■ मधुमक्खी का डंक तकलीफ देने के साथ-साथ अपने शिकार का हुलिया भी ऐसे बिगाड़ देता है कि बेचारा कम-से-कम कुछ दिन के लिए तो किसी को अपना मुंह दिखाने की हालत में नहीं रहता.

लेकिन पिछले दिनों पंजाब के जैतो मंडी इलाके में मधुमक्खियों के एक झुंड ने जो गुल खिलाया उसने गांव भर के लिए एक हास्यास्पद हालत पैदा कर दी.

एक मृत व्यक्ति का दाहसंस्कार करने के सिलसिले में गांव के लोग इकट्ठे हुए. कंधों पर अर्थी लिए शवयात्रा श्मशान घाट की ओर बढ़ चली. मृतक की याद में उदास लोगों का यह समूह अभी श्मशान घाट के निकट पहुंचा ही था कि एक अजीबोगरीब घटना हो गई. नजदीक ही एक पेड़ पर मधुमक्खी का एक छत्ता लटक रहा था जिस पर निशाना साधकर कुछ शरारती लड़के ढेले फेंक रहे थे. अचानक एक ढेला निशाने पर जा लगा और छत्ता फूट गया. आतंकित मक्खियों का झुंड भिनभिनाता हुआ हवा में फैल गया. इसी बीच लड़के तो वहां से भाग लिए पर मधुमक्खियों के झुंड ने नीचे से गुजर रहे शवयात्रियों पर हमला बोल दिया. इस अचानक हमले से घबराए अधिकांश लोग अर्थी को वहीं छोड़ भाग खड़े हुए. लेकिन जल्दी भाग पाना उन लोगों के लिए संभव नहीं था जो अर्थी को कंधा दिए हुए थे. इसी बदहवासी के मारे उनमें से कई लोगों ने मधुमक्खियों की मार से बचने के लिए कफन की चादरें खींचकर अपने ऊपर ओढ़ लीं.

शहंशाह भिखारी

■ भीख मांगने का व्यवसाय सबसे पुराने व्यवसायों में से है. भीख मांगने वालों ने जो तरीके ईजाद किए हैं उनका यदि ग्रंथ तैयार किया जाए तो यकीनन दुनिया के बड़े से बड़े महाकाव्य भी मात खा जाएं. पिछले दिनों कानपुर के एक भिखारी के किस्से ने इस शृंखला में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है.

कानपुर के कुछ इलाकों की गृहिणियां इस भिखारी से इतनी परेशान हैं कि उनसे न तो उसे भीख देते बनता है और न मना करते. इस मजबूरी का कारण यह है कि यह कोई छोटा-मोटा भिखारी नहीं बल्कि खासे 'रुतबे' वाला भिखारी है. कपड़ों से वह भले ही फटेहाल रहता है पर भीख मांगने के लिए वह किसी राजा-महाराजा की तरह हाथी पर सवार होकर आता है. सिर्फ इतना ही नहीं, भीख भी वह देने वाले की मर्जी से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से लेता है. घर के दरवाजे पर हाथी खड़ा देखकर भौचक हुई बेचारी गृहिणी को भिखारी की मर्जी के मुताबिक पैसा, आटा, दाल या चावल देना ही पड़ता है वरना भिखारी और उसका हाथी वहां से हिलने का नाम ही नहीं लेते. और मजेदार बात यह है कि यह हाथी उसका अपना नहीं बल्कि किसी और का है. वह दिन में केवल तीन-चार घंटे

के लिए हाथी और उसके महावत को साथ लेकर चलता है. 'दिहाड़ी' पूरी होने के बाद भीख में मिला आधा माल महावत को देकर वह अपना हिस्सा लेकर चलता बनता है.

संकलन: विजय क्रांति

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हाथ का हौवा

विदेशी हाथ का हौवा हावी रहा बीते पखवाड़े पर. और पहली बार लगा कि यह हौवा बहुत बेबुनियाद भी नहीं है. पंजाब में पाकिस्तानी पिट्ठुओं की कारस्तानियों को लेकर भारत सरकार की अरसे से चली आ रही तोतारटंत तब अचानक तीखी और पुरअसर लगने लगी जब इस आतंकग्रस्त राज्य में रोजाना होने वाली मौतों की तादाद और जानलेवा अत्याधुनिक हथियारों की आमद बेहिसाब बढ़ गई. प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चेतावनी तो दी कि भारत को मजबूरन जवाबी कार्रवाई करनी पड़ सकती है लेकिन उनकी इस चेतावनी के पीछे किसी तरह का संकल्प नहीं दिखा. वैसे भारतीय विदेश विभाग ऐसी चेतावनियों को दमदार बनाने पर गंभीरता से विचार करता दिख रहा है.

सभी रेखाचित्र: पिअली दत्त गुप्ता

राजीव ने पंजाब के मामले में पाकिस्तान को चेतावनी दी. और कांग्रेस सम्मेलन में भी उनके तेवर तीखे दिखे

लेकिन जो विदेशी हाथ अब बोफोर्स घोटाले के पीछे लगभग साफ दिख रहा है उससे निबटना सरकार के लिए शायद आसान नहीं होगा. मद्रास के अखबार ने इस घोटाले से संबंधित जो सनसनीखेज सबूत छापे हैं उनसे साफ लगता है कि उस सौदे में दलाली स्विस बैंक के जिन तीन खातों के जरिये अदा की गई उनमें से एक खाते का संबंध लंदन स्थित हिंदुजा घराने से है. इस तरह घोटाले से एक परदा तो हट गया लगता है. और हिंदुजा की ओर से तुरतफुरत जारी खंडन अखबार में छपे दस्तावेजी सबूतों के आगे फीके ही लगते हैं. इस विवादास्पद व्यावसायिक घराने के जो ऊंचे ताल्लुकात हैं भारतीय शासकों से, और रहस्योद्घाटन के बाद सरकारी हलकों में जो दहशत-सी फैली है उनसे तो यही लगता है कि तवा उम्मीद से कहीं ज्यादा गरम है.

मद्रास के एक अखबार ने जो सनसनीखेज सबूत छापे उनसे साफ है कि बोफोर्स सौदे में दलाली जिन स्विस बैंक खातों में जमा की गई उनमें से एक का संबंध हिंदुजा परिवार से है

लेकिन विचित्र विसंगति तो यह है कि बोफोर्स घोटाले की जांच करने वाली 30 सदस्यीय संसदीय समिति करीब 50 बैठकों में करीब 15 महत्वपूर्ण गवाहों से 200 घंटे से ऊपर जिरह करके करीब 400 पन्ने की रिपोर्ट देती है. और साफ फैसला सुनाती है कि होवित्जर की खरीद में कोई गैरकानूनी भुगतान नहीं किया गया—किसी भारतीय को तो नहीं ही. अब सरकार आरोपों से उबरने की बेमतलब उछलकूद में लगी है.

और उधर तमिलनाडु के कामराज नगर में कांग्रेस अधिवेशन में हुई उछलकूद भी बहुत सार्थक नहीं दिखी. विपक्ष पर जम कर की गई बौछार. राजीव और उनके चाटुकारों ने वही पुराना राग अलापा कि सभी गैर इंकाई मुख्यमंत्री सिद्धांतहीन हैं और देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं. लेकिन ये सभी बयान इतने घिसे-पिटे हैं कि कतई विश्वसनीय नहीं लगे. ऐसा ही घिसा-पिटा लगा गरीबी हटाओ की तर्ज पर दिया गया नया नारा 'बेकारी हटाओ'. आडंबरों के प्रति मंत्रमुग्ध सरकार के मुंह से ऐसे नारे खोखले ही लगते हैं.

इस अधिवेशन के तमाम तेवर तो यही संकेत देते दिखे कि केंद्र और गैर-इंका शासित राज्यों में टकराव आगे और तीखा ही होने वाला है. 32 वर्षों बाद तमिलनाडु में अधिवेशन करना दुश्मन के खेमे में घुसकर युद्धघोष करने का प्रतीक ही लगा. लेकिन सत्ता पार्टी अगर सोचती है कि इस युद्ध में उसका ही पलड़ा भारी रहेगा तो शायद वह मुगालते में है. उसका पहला गोला—मुख्यमंत्री नंदमूरि तारक रामराव को आयकर मामले में अदालत में घसीटना—फुसफुसा ही साबित हुआ है. रामराव ने अपनी अनूठी अभिनय क्षमता के बूते इस हमले को नाकाम ही नहीं किया बल्कि पांसा पलट भी दिया.

मुख्यमंत्री रामराव को आयकर मामले में अदालत में घसीटना इंका के लिए उलटा ही पड़ा

उधर उगते सूरज के देश जापान में भी ऐसी ही अभिनय क्षमता का प्रदर्शन किया राजीव ने, जहां भारत महोत्सव का एक और प्रकरण प्रारंभ हुआ. सांस्कृतिक समारोह से समय निकालकर राजीव ने जापानी उद्योगपतियों को कायल करने का भी काम किया और भारत में उनके भारी पूंजी निवेश की नींव डाली. उम्मीद है कि इस पर एक अच्छी इमारत खड़ी होगी. वैसे, कूटनीति की करिश्माई उपलब्धि राजीव के साथ जापान यात्रा करने वाले उनके वरिष्ठ सहयोगी विदेश राज्यमंत्री के. नटवर सिंह के खाते में आई. वे भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए.

—दिलीप बॉब

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इंका अधिवेशन

नेता के आगे नतमस्तक

माना जा रहा था कि हाल ही में मद्रास के करीब इंका महासमिति के हुए दो दिन के अधिवेशन में घोटालों, अंदरूनी असंतोष और राजनैतिक उलटफेर से त्रस्त पार्टी आत्म समीक्षा की जद्दोजहद से गुजरेगी. पर इस मौके पर कई आश्चर्यजनक तथ्य सामने आए. पार्टी अप्रत्याशित आत्मविश्वास से लबालब दिखी. अधिवेशन स्थल पर लगे आदमकद चित्रों के ऐन मुताबिक राजीव गांधी पार्टी के लिए एकदम देवता बनकर ही उभरे. अधिवेशन की रिपोर्ट—वरिष्ठ संपादक प्रभु चावला **और वरिष्ठ संवाददाता** एस.एच. वेंकटरमनी **की कलम से:**

कुल मिलाकर यह राजीव का सम्मेलन था. हर तरफ उनका ही बोलबाला था. खुशामदियों की बाढ़ सी आ गई थी. नारेबाजों की बन आई. दबंग लोगों को धमका दिया गया. नए नेता फूले न समा रहे थे. पुराने महारथियों को नकेल डाल दी गई. गर्ज कि मद्रास से 50 किलोमीटर दूर मरैमलै नगर नामक धूलधूसरित शहर में पिछले पखवाड़े इंका महासमिति के दो दिवसीय अधिवेशन में आए 5,000 इंका प्रतिनिधियों में से करीब हर कोई वस्तुतः राजीव गांधी के समक्ष दंडवत हो गया था. असंतोष का कहीं कोई नामोनिशान न था.

चुनावी पराजयों, पार्टी से निष्कासनों, जनमोर्चा की ओर से चुनौती, रक्षा घोटालों, मंत्रिमंडल में कई फेरबदलों और मुख्यमंत्रियों की छंटाई के बावजूद इंका राजीव की निर्विवाद अगुआई में अटल स्तंभ जैसी दिखी.

ऐसा ही मिजाज '70 के दशक के अंत में इंका महासमिति के गुवाहाटी और चंडीगढ़ अधिवेशनों में इंदिरा गांधी की कांग्रेस ने प्रदर्शित किया था. उन्हीं दिनों देवकांत बरुआ ने 'इंदिरा ही भारत है' का नारा दिया. मरैमलै नगर में भी पार्टी के दिग्गज इसी किस्म का नारा गढ़ने में दीवानगी से लगे रहे. उन्होंने नया नारा निकाला भी—'राजीव का युग'. 1985 के मुकाबले अब की बार तेवर भी बदल गए थे. तब ऐसा ही अधिवेशन बंबई में हुआ था.

बंबई में उन्होंने पार्टी नेताओं को 'सत्ता के दलाल' कहकर फटकारा था. लेकिन मद्रास में उन्होंने इंका नेताओं को न्याय के अगुआ और मजलूमों के रखवाले जैसी संज्ञाएं देकर गौरवान्वित किया. उन्होंने घोषणा की, "कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो गरीबों और मजलूमों से जुड़ी हुई है, बेसहारा और दबे-कुचलों के अधिकारों की खातिर लड़ती है तथा भारत को राष्ट्रीय विकास के पथ पर ले जा रही है. कांग्रेस ही असूलों वाली एकमात्र पार्टी है."

पार्टी के प्रति इस नई प्रेम भावना का प्रत्युत्तर भी नेता की इस कदर चाटुकारिता के रूप में मिला कि कांग्रेस पार्टी व्यक्ति पूजा को फिर से उभारने की राह पर चलती नजर आने लगी. तीन-पेजी राजनैतिक प्रस्ताव में प्रधानमंत्री का स्तुतिगान करने के लिए उसे तीन बार बदला गया. उसमें प्रधानमंत्री के तीन वर्षीय शासन का जिक्र ऐसे मिशन के रूप में है जिसमें "भारत की प्राचीन विरासत की बड़े जतन से रक्षा की गई और तकनीक को आम आदमी की खिदमत में लगाया गया. यही कांग्रेसी विचारधारा है... राजीव युग लोगों के बेहद ठोस समर्थन पर आधारित अपूर्व राजनैतिक स्थिरता का युग है."

व्यक्ति पूजा को पुनर्जीवित किए जाने का सीधा असर यह हुआ कि वे कांग्रेसी नेता निस्तेज पड़ गए जिनका अपना ठोस राजनैतिक आधार है. बंबई अधिवेशन के दोनों प्रबंधकों अरुण सिंह और अरुण नेहरू की जगह एक नई त्रिमूर्ति ने ले ली थी. मद्रास में किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात के लिए कांग्रेस श्रद्धालुओं की भीड़ सीताराम केसरी, गुलाम नबी आजाद और वासुदेव पणिक्कर की ओर मुखातिब दिखती थी. एक अन्य महासचिव ऑस्कर फर्नांडीस की पूछ भी थी पर उनसे जरा कम. दो साल पहले महासचिवों की औसत उम्र 50 साल से ऊपर हुआ करती थी. आज उनमें आधे 50 से कम उम्र के हैं. वे नेता के फैसलों को बजा लाने के लिए हुई प्रत्येक महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित रहे. अधिवेशन में राज्य स्तर के दूसरे उभरते हुए नेताओं में तारिक अनवर, अशोक गहलोत, अहमद पटेल और दर्जन भर नौजवान प्रदेश इंका अध्यक्ष भी महत्वपूर्ण रहे.

झंडे को सलामः एकता का प्रतीक

सभी फोटो भवान सिंह

इंका कार्यसमिति के गठन से भी नई संगठन व्यवस्था का इजहार हुआ. हालांकि जे. वेंगलराव, कृष्णचंद्र पंत और वसंत साठे सरीखे वरिष्ठ मंत्री मंच पर बिराजमान थे पर रक्षा राज्यमंत्री संतोषमोहन देव, गृह राज्यमंत्री पी. चिदंबरम और विदेश राज्यमंत्री नटवर सिंह जैसे जूनियर मंत्रियों को न सिर्फ महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर बोलने के लिए चुना गया बल्कि अहम मामलों में उनसे विचार-विमर्श भी किया जाता रहा. राजीव ने रघुनंदनसहाय भाटिया, नजमा हेपतुल्ला, नवल किशोर शर्मा आदि जैसे पूर्व मंत्र

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सफर का आखिरी हिस्सा रेलगाड़ी से तय करके पहुंचे राजीव का भव्य स्वागत हुआ. मैदान में कांग्रेस नेताओं के आदमकद चित्र लगे थे

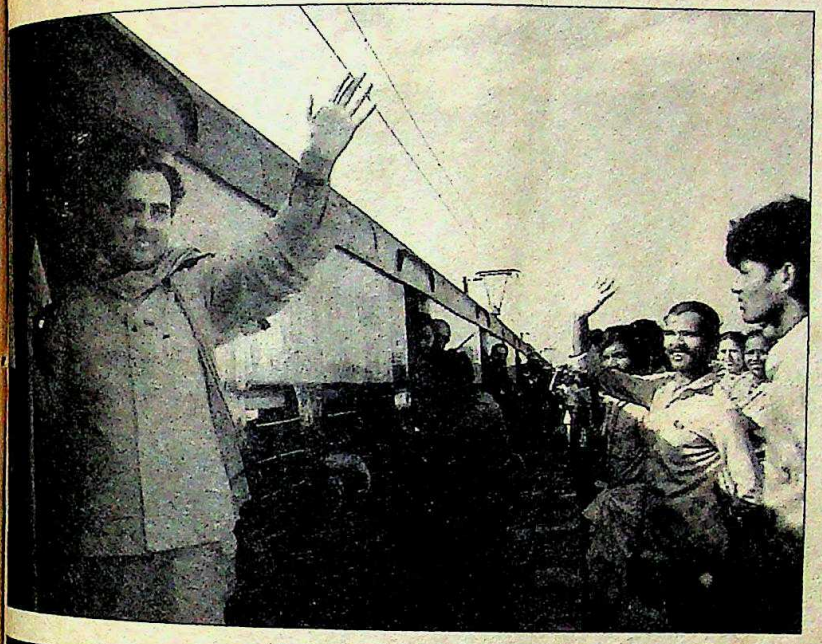

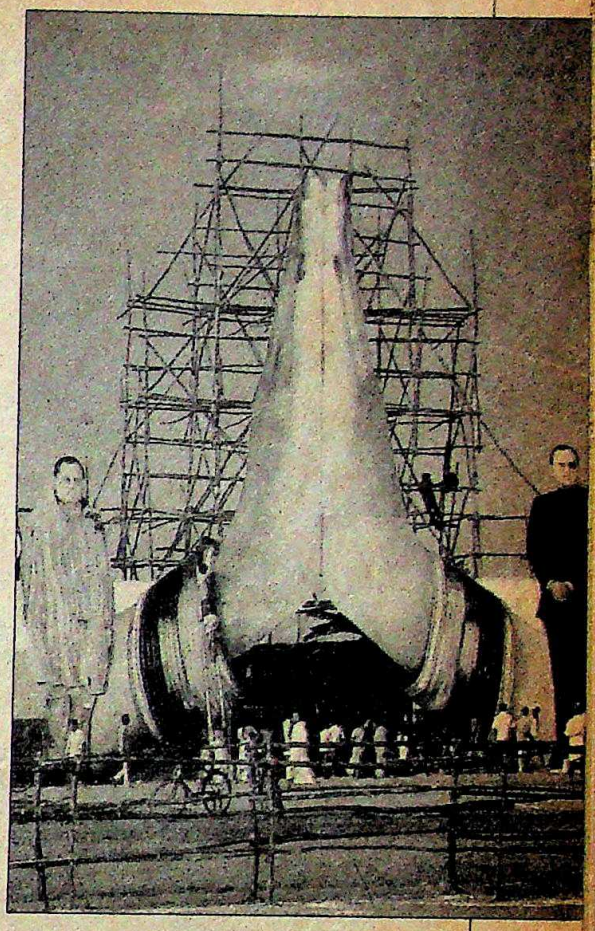

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

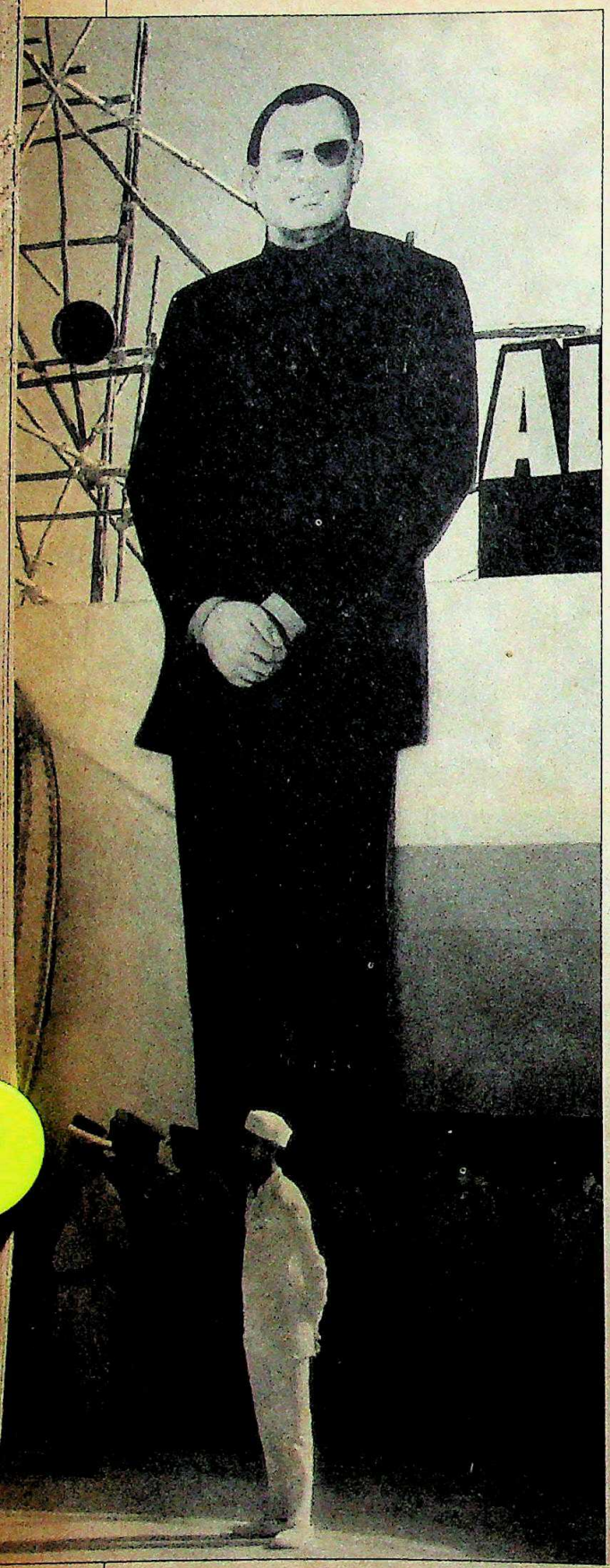

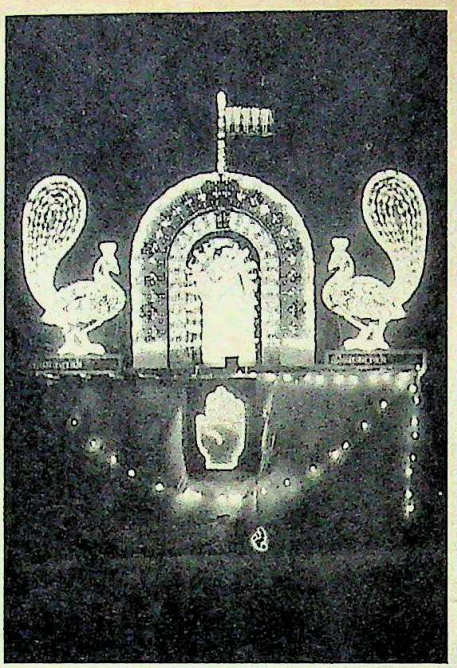

खुशामदियों, नारेबाजों की बन आई. लगभग हर शख्स राजीव गांधी के समक्ष दंडवत हो गया. असंतोष का कहीं नामोनिशान न था

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तमिल फिल्मों वाली शैली में ही अधिवेशन स्थल को एकदम चटख रंगों के पोस्टरों और रंग-बिरंगे झंडों से सजाया गया था

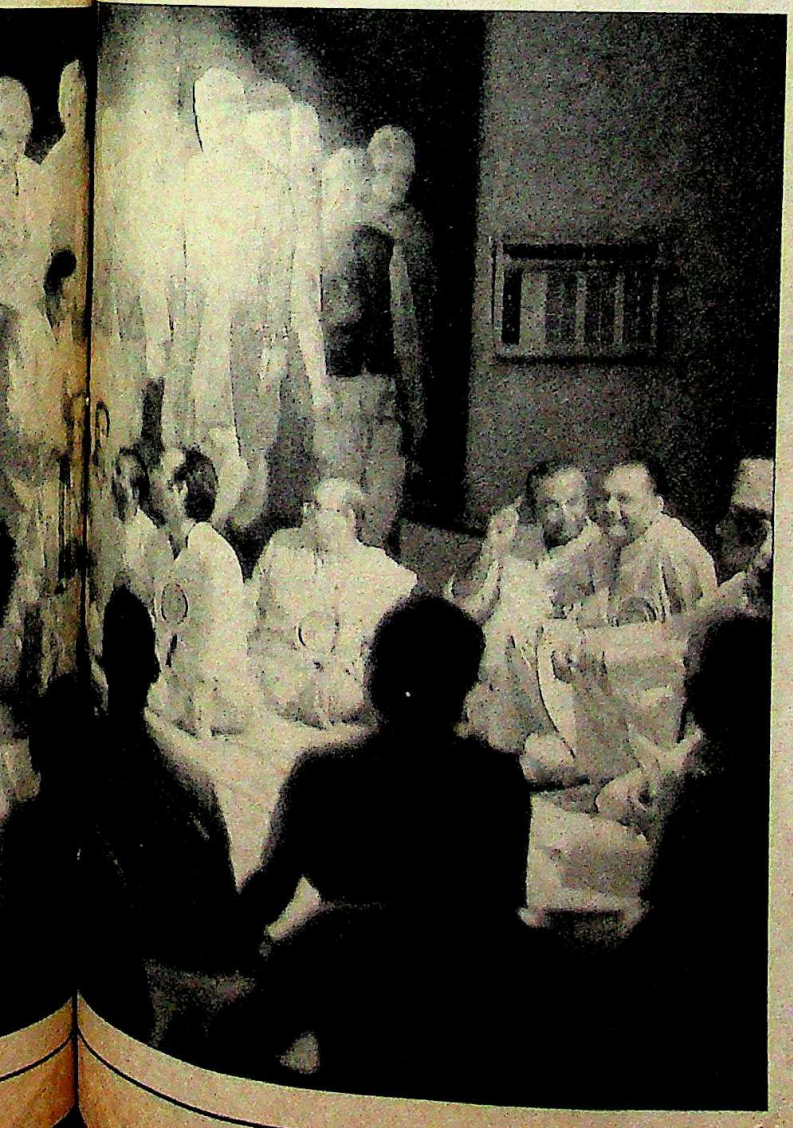

श्याम टेकवानी

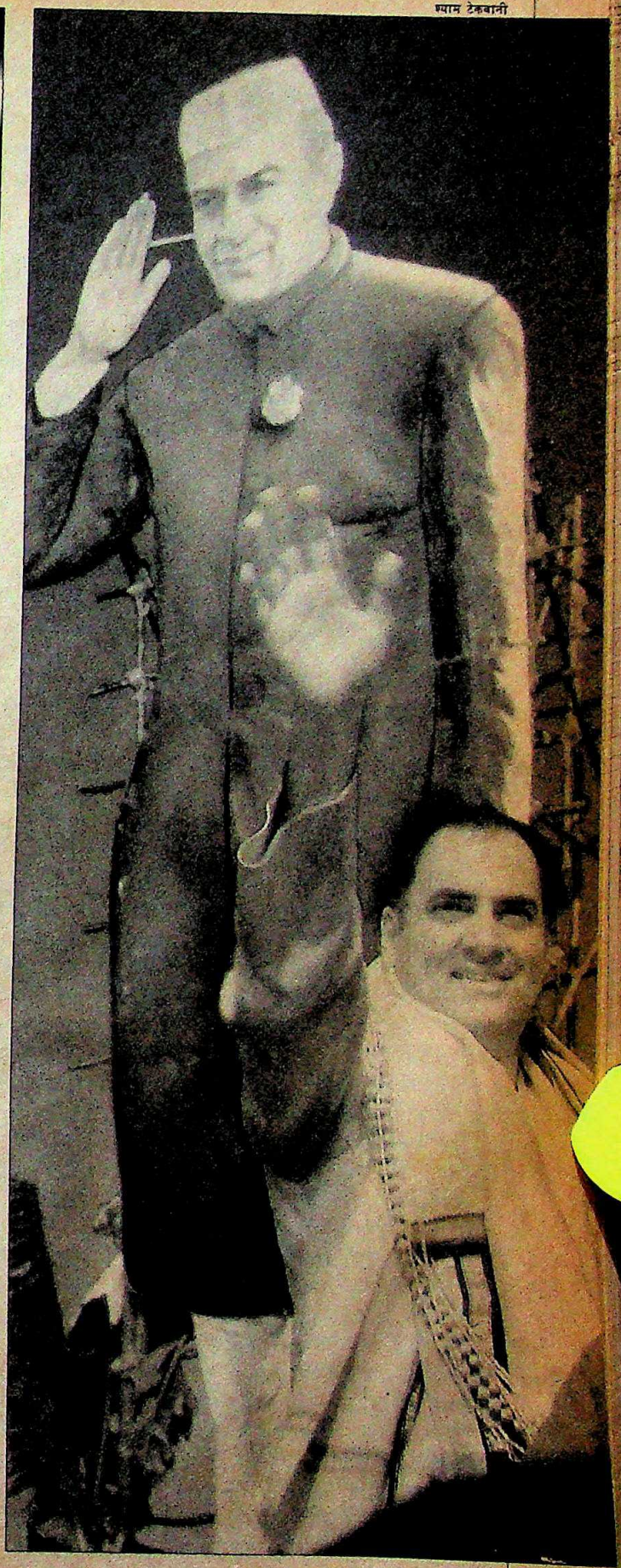

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

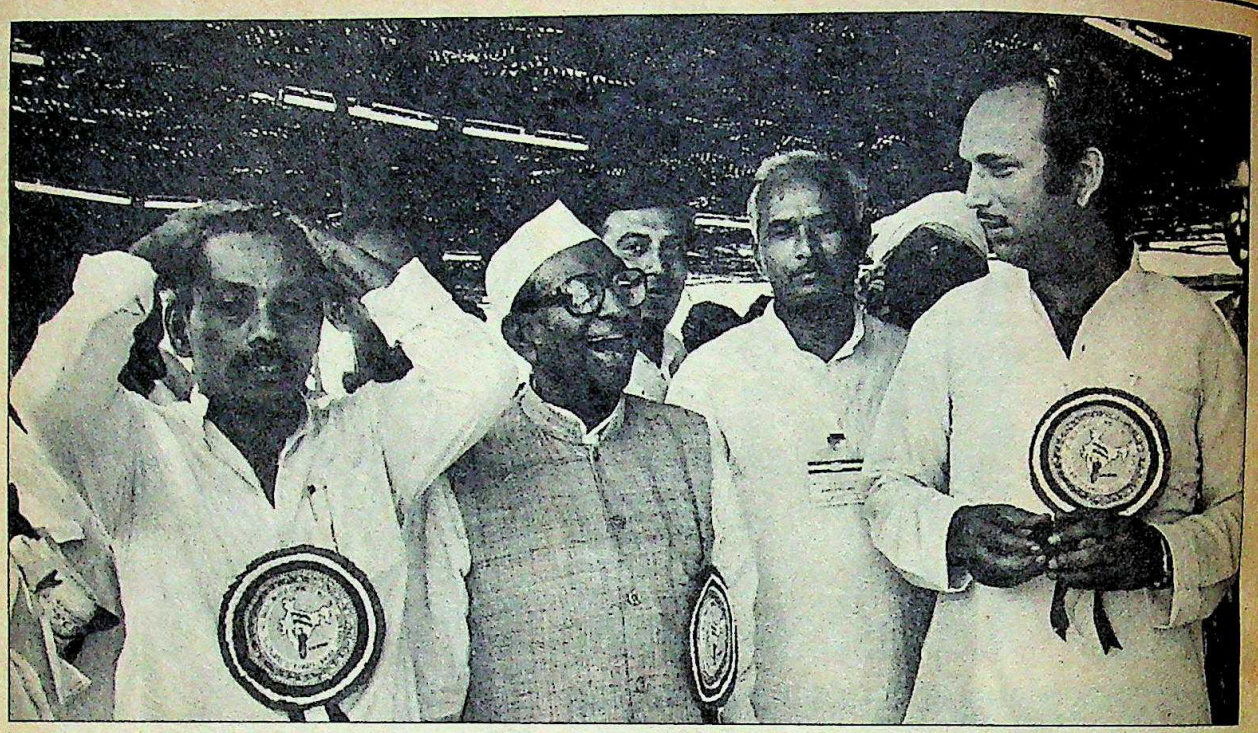

(बाएं से) पणिक्कर, केसरी और गुलाम नबी (दाएं): नई त्रिमूर्ति

सचिवों को तो कतई दरकिनार किया. वे महासमिति के आम सदस्यों के बीच बैठे रहे.

प्रधानमंत्री की प्रशंसा के पुल बांधने की होड़ में अनोखे तरीके ढूंढ निकाले गए. मध्य प्रदेश के सांसद बालकवि बैरागी ने इसके लिए एक कविता रच डाली. अभिनेत्री से नेता बनी वैजयंती माला ने मंच से 'राजीव जिंदाबाद' के अनेक नारे लगाए. अर्जुन सिंह ने राजीव को 'प्रत्येक क्षेत्र में भारत की सफलता की एकमात्र कुंजी' बताया. कोषाध्यक्ष सीताराम केसरी ने हुंकार लगाई, "राजीव के साथ देश का भाग्य जुड़ा हुआ है. अगर वे हतोत्साहित हो गए तो देश भी हतोत्साहित हो जाएगा. जो लोग युवा प्रधानमंत्री को बदनाम करने पर तुले हुए हैं, हमें उन सभी को पार्टी से तुरंत निकाल बाहर करना चाहिए."

पार्टी पूरी तरह राजीव के नियंत्रण में है, इसका सबूत यह है कि वे वरिष्ठ नेताओं को विपक्ष पर परंपरागत आक्षेप करने से रोक पाने में कामयाब रहे. इसके बजाय राजीव ने उन्हें पार्टी से निष्कासित लोगों खासकर विश्वनाथ प्रताप सिंह और साथ में ज्ञानी जैल सिंह के खिलाफ विद्वेषपूर्ण और निंदात्मक हमला करने के लिए मना लिया. केंद्रीय गृहमंत्री बूटा सिंह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह को पार्टी के पुराने साथियों पर हमले की अगुआई करने के लिए चुना गया. बूटा सिंह ने गरजते हुए कहा, "राष्ट्रपति भवन सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक अड्डा बन गया. वहां विदेशी मुद्रा विनियमन कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों, तस्करों और घोषित अपराधियों को पनाह मिलने लगी." उनके राज्यमंत्री पी. चिदंबरम ने व्यंग्यबाण छोड़ा, "राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति भवन के प्रधान सूचना अधिकारी नहीं."

राजनैतिक प्रस्ताव में देरी होने की एक वजह यह भी थी कि वी.पी. सिंह पर कड़ा प्रहार दर्ज करने के लिए इसमें कई बार संशोधन किए गए. उन्हें 'झूठ का मसीहा' बताया गया. अर्जुन सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बीरबहादुर सिंह ने उन्हें 'कांग्रेस के इतिहास में सबसे बड़ा विश्वास-घाती' करार दिया. बीरबहादुर ने कहा, "विश्वनाथ प्रताप से बड़ा बेईमान इस देश में नहीं हुआ. हमें उनसे देश को बचाना है."

पार्टी को संसदीय चुनावों के लिए तैयार करने के अलावा महासमिति के अधिवेशन का मकसद तमिलनाडु में इंका का मनोबल बढ़ाना भी था. तमिलनाडु के पार्टीजनों को प्रतिनिधियों को संबोधित करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया. प्रधानमंत्री ने रेलगाड़ी के दूसरे दर्जे के डिब्बे में 40 किलोमीटर से अधिक की यात्रा की. मकसद यह था कि रेलवे पटरी के दोनों ओर स्वागत करते लोग उनकी झलक पा सकें. मगर कुछ स्थानों को छोड़ भीड़ कम थी.

बाद में अधिवेशन में उन्होंने राज्य के लिए 1500 करोड़ रुपए की एक विशेष विकास योजना की घोषणा की. उनके समापन भाषण का अनुवाद चिदंबरम ने तमिल में किया जिसे सुनने के लिए करीब 50,000 लोग 3.5 लाख वर्गफुट के घेरे में बने सुंदर-से पंडाल में जमा हुए थे. तमिल फिल्म परंपरा की शैली में मद्रास से अधिवेशन स्थल तक का समूचा 40 किलो-मीटर मार्ग गांधी, कामराज, नेहरू, राजीव, इंदिरा और प्रदेश इंका अध्यक्ष जी.के. मूपनार के बड़े-बड़े लकड़ी के चित्रों से सजाया गया था. कांग्रेस की रणनीति इस क्षेत्र में कामराज का नाम भुनाने की है, यह मूपनार के भाषण से स्पष्ट हो गया. उन्होंने कामराज के मुख्यमंत्रित्व काल को तमिल-नाडु के सुनहरे युग की संज्ञा दी. इस पर द्रमुक के एक कार्यकर्ता की टिप्पणी थी, "वे हमेशा दिवंगत नेताओं के नाम पर चुनाव जीतना चाहते हैं. मेरा ख्याल है तमिलनाडु में उनके हाथ निराशा ही लगेगी."

अधिवेशन के दौरान पार्टी में नारों और शब्दाडंबरों का दौर लौट आने के लक्षण भी दिखे. स्पष्ट है कि जहां राजीव ने अब पार्टी को अपना बंधक बना रखा है, वहीं वे भी पार्टी के बंधक बन गए हैं; उसी व्यवस्था का अंग बन गए हैं जिसके खिलाफ बंबई में उन्होंने आवाज उठाई थी. जिस शख्स के बारे में कहा जाता था कि वह 'बाद' के नाम पर सिर्फ व्यावहारिकतावाद पर यकीन रखता है, अब अधिवेशन के दौरान दक्षिण-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नहीं है. यह कौन सा समाजवाद है जहां सरकार अपने बिलों का भुगतान नहीं कर सकती, दो-तीन महीने तक अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे सकती? अगर कोई राज्य सरकार अपने हितों के लिए अपने यहां हुए पूंजीनिवेश को बेच डाले तो मैं उसे समाजवाद हरगिज नहीं कहूंगा. कांग्रेस यह काम कभी नहीं करेगी."

लेकिन दिल्ली लौटने से पहले एक प्रेस कांफ्रेंस में राजीव से पूछा गया कि तमिलनाडु की लोकप्रिय योजनाओं के बारे में उनका क्या ख्याल है. उनका जवाब था, "दिवंगत रामचंद्र द्वारा शुरू की गई दुपहरी भोजन की योजना जैसी लोकप्रिय योजनाएं राष्ट्रपति शासन में बंद नहीं की जाएंगी."

विरोधाभासों के बावजूद अधिवेशन से जाहिर हुआ कि पार्टी के नए नेताओं ने अपने अध्यक्ष की सबसे दुलारी उच्च तकनीक को पार्टी का संचालन करने में भी अपना लिया है. समूचा आयोजन कंप्यूटरों की मदद से पूरा हुआ. पार्टी पुराने किस्म की टेलीफोन व्यवस्था पर निर्भर नहीं रही. जयंती नटराजन और रंगराजन कुमारमंगलम सरीखे राज्य इंका के पदाधिकारियों तथा केंद्रीय राज्यमंत्री पी. चिदंबरम को न सिर्फ पार्टी नेताओं बल्कि स्थानीय अधिकारियों से भी संपर्क करने के लिए बाकी-टाकी मुहैया कराए गए थे.

तमिलनाडु इंका ने अपने कुछ युवा समर्थकों की एक स्थानीय कंपनी की सेवाएं ले रखीं थी. उन लोगों ने तमिलनाडु के आगामी चुनावों के संचालन के लिए सॉफ्टवेयर ही तैयार नहीं किए बल्कि अधिवेशन स्थल पर वे छपाई की दो छोटी ऑफसेट मशीनें भी लाए थे. एक कंप्यूटर सेंटर स्थापित किया गया था जहां प्रस्ताव और भाषण छापे गए. इसीलिए जब राजीव ने सांसद कुमारमंगलम को 40 मिनट में अपने भाषण की 200 प्रतियां छापने का आदेश दिया तो कोई दिक्कत नहीं आई. भाषण का अंतिम रूप सूचना व प्रसारण मंत्रालय के सलाहकार सुमन दुबे द्वारा अनुमोदित किए जाने और राजीव के भाषण शुरु होने से कुछ मिनट पहले कुमारमंगलम को दिया गया था.

अधिवेशन की समाप्ति तक एक बात साफ हो चुकी थी कि इंका अब नेता की ही मानने के युग में पहुंच गई है.

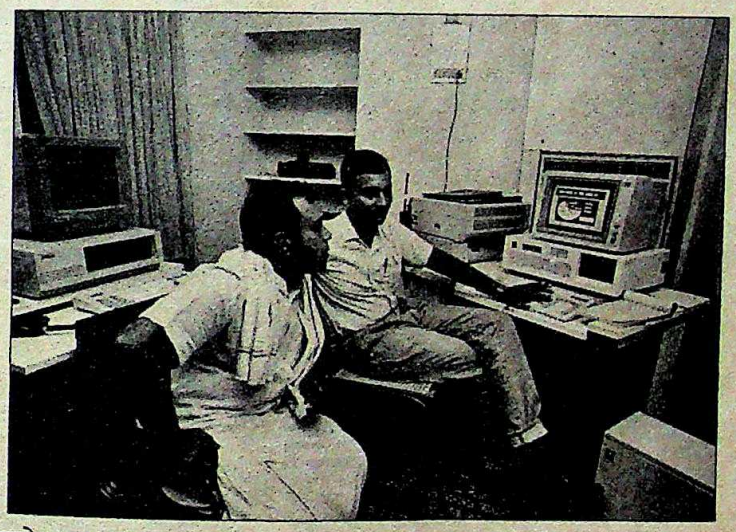

(ऊपर से) नटराजन; रंगराजन (बाएं); और चिदंबरम: राजनीति में तकनीक

नूसी विचारों, पीठ पीछे बुराई और कठमुल्लावादी भाषणों को सुनता रहा और उन पर तालियां पीटता रहा. पर्वधित इंका कार्यसमिति के 120 से अधिक सदस्यों ने शुरुआती सत्र की कार्रवाई में भाग लिया. पश्चिम बंगाल इंका के उग्र नेता प्रियरंजन दासमुंशी ने समाजवाद की वकालत करते हुए पार्टी को वैचारिक आधार पर दिशा देने की जरूरत पर जोर दिया. पर केंद्रीय ऊर्जामंत्री वसंत साठे सरीखे लोग भी थे जिन्होंने सरकारी क्षेत्र और दूसरे तथाकथित समाजवादी पगों' का उपहास उड़ाया. इस पर बिहार के मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद ने उन पर आवाजें कसीं. मगर इस बात पर सभी एकमत थे कि पार्टी को अगले चुनावों के लिए किसी नारे की जरूरत है. उनका कहना था कि उनके पास राजीव गांधी के रूप में करिश्माई नेता तो है पर किसी नारामंद जादुई मंत्र का अभाव है. दो घंटे से अधिक की माथापच्ची के बाद पैसला हुआ कि बेरोजगारी को मुख्य मुद्दा बनाया जाए. साठे और बंबई इंका अध्यक्ष मुरली देवड़ा ने तत्काल सुझाव दिया कि पार्टी को बेकारी हटाओ' जैसा नारा लाना चाहिए. इसे तुरंत मंजूर कर लिया गया. पर कुछ लोगों का मत था कि इस नारे के साथ गरीबी हटाओ का नारा भी जोड़ लिया जाए. इस पर पार्टी ने गरीबी हटाओ, बेकारी हटाओ' का नारा चुन लिया. इसके अलावा समाजवाद और सरकारी क्षेत्र पर भी अटल विश्वास जाहिर किया गया.

प्रधानमंत्री ने विपक्ष शासित राज्यों द्वारा लोकप्रिय योजनाओं पर फिजूलखर्ची करने की आलोचना करते हुए वर्षों पुरानी कांग्रेसी परंपरा निभाई. पर वे अपने ही फंदे में फंस गए क्योंकि अगली ही सांस में उन्हें तमिलनाडु में लोकप्रिय योजनाओं को चलाने की जरूरत का पक्ष लेना पड़ा. अधिवेशन का समापन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, "हमारे यहां बहुत सी सरकारें मुफ्तखोरी भोजन, कपड़े, चप्पलें और बिजली तो मुहैया कराती हैं पर उनके पास अपने बिलों का भुगतान करने या अपने कर्मचारियों तक को वेतन देने के लिए पैसा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उषा आज! उषा अब!

सुनहरे व भूरे सरताज: कोहिनूर सुपर डीलक्स, सेनेटर और नया सजीला तीन-ब्लेड पल्सर.

चमकते दमकते मोतियों से सफ़ेद. स्टैला, पल्सर, प्राइमा.

उषा के विस्तार का जवाब नहीं. विलासपूर्ण आराम भी, आसान दाम भी. हर पसंद, हर डिज़ाइन के पंखे.

और कई दूसरे आकर्षक सितारे भी–तरह-तरह के टेबिल, वॉल, कैबिन, पैडेस्टल और वेंटिलेटिंग पंखे. उषा की उत्तम तकनीक से गढ़े, दुनिया के पारखी लोगों के लिये उषा पंखे–रूप उत्तम, बिकें अधिकतम.

पल्सर डेकोरेटिव

पल्सर एक्सपोर्ट

कोहिनूर सुपर डीलक्स

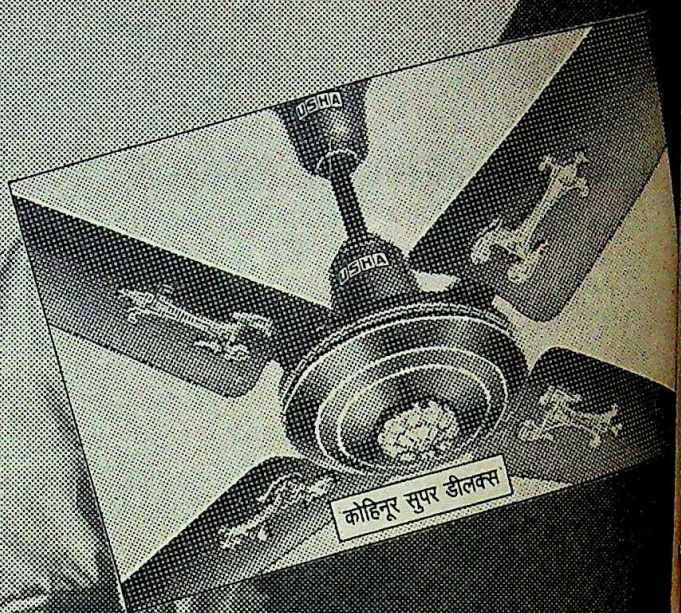

महलों का सरताज

U S H A उषा

भारत का सर्वाधिक बिकने वाला पंखा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बोफोर्स जांच

पाक-साफ दिखाने की कोशिश

संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट तथ्यों से कतई मेल नहीं खाती

"आप हमें कोई सबूत दिखाइए कि बोफोर्स सौदे में बिचौलिये थे और उन्हें कोई भुगतान या रिश्वत या दलाली दी गई. तभी हम कार्रवाई करेंगे और देखेंगे कि किसी को भी बख्शा नहीं जाए."

—राजीव गांधी, लोकसभा, 20 अप्रैल '87

इस 'प्रधानमंत्रीय' उद्घोष के साल भर बाद बोफोर्स घोटाले की जांच-पड़ताल करने वाली संयुक्त संसदीय समिति ने पिछले सप्ताह अपनी रिपोर्ट पेश कर दी. इसके मुताबिक 155 मिमी वाली 400 बोफोर्स तोपों का 1,700 करोड़ रुपए का सौदा बिलकुल 'पाक-साफ' था. रिपोर्ट के अनुसार सरकार को यथासंभव बेहतर शर्तों पर सर्वोत्तम तोपें मिलीं. सौदे की बातचीत में कभी कोई दलाल शामिल नहीं था. और इस बात के भी सबूत नहीं हैं कि बोफोर्स ने "करार समेटने के लिए' इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड और पनामा की जिन तीन कंपनियों को जो रकम दी, उनसे कोई भारतीय भी जुड़ा था.

लेकिन समिति की मुसीबत बस एक ही है. उसकी रिपोर्ट पर कोई भी भरोसा करता नहीं दिख रहा. इसके दो कारण हैं. एक तो है असहमति वाली वह टिप्पणी जो अन्नाद्रमुक (जानकी गुट) सांसद अलादि अरुणा ने रिपोर्ट के साथ नत्थी करवा दी है. और दूसरा कारण रिपोर्ट में दर्ज तथ्यों का रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों से मेल नहीं खाना है.

और यह सवाल जस का तस कायम है कि सौदे के सिलसिले में जिन तीन कंपनियों को 31.94 करोड़ स्वीडिश क्रोनर (करीब 64 करोड़ रु.) दिए गए, उनके पीछे कौन लोग थे और उन्होंने बोफोर्स को क्या सेवाएं दीं.

समिति के निष्कर्षों में कई खामियां मिली हैं. सेना ने तय किया था कि उसे 28 से 30 किमी तक मार करने वाली तोपें चाहिए. लेकिन सौदा तय करने से पहले बोफोर्स तोपों का भारत में जब परीक्षण किया गया तो ये मुश्किल से 21 किमी तक गोला फेंक पाई थीं. फिर सेना ने इस दावे को मान लिया कि बाद के परीक्षणों में इन तोपों से 29 किमी तक गोले फेंके गए. सेना ने कहा कि यह दावा बोफोर्स कंपनी का है और वही इसके लिए जिम्मेवार होगी.

संयुक्त संसदीय समिति के मुताबिक तो बोफोर्स तोप सस्ती थी पर अन्नाद्रमुक सांसद अलादि अरुणा की विमत टिप्पणी इसका खंडन करती है

दरअसल, सौदे को अंतिम रूप दिए जाने से पहले सेना की पसंद फ्रांस की सोफ्मा कंपनी द्वारा निर्मित तोपें थीं. लेकिन मार्च 1986 में अंतिम फैसला करने से एक महीना पहले सेना ने बोफोर्स तोपों को तरजीह दे दी. जनरल के. सुंदरजी ने सेना के इस फैसले को समिति के सामने यह कहते हुए सही ठहराया कि बोफोर्स की गोला

ऐसे आया और वैसे गया पैसा

एबी बोफोर्स

18.84 करोड़ क्रोना (37.7 करोड़ रुपए)

स्वेंस्का इनकार्पो.
10, एल्विरा मिडास स्ट्रीट
इंटरसेको बिल्डिंग
पनामा 5

सामान्य परामर्श समझौता, 1978
जिसमें भारत सहित दूसरे एशियाई देश भी शामिल हैं
बिक्री पर कमीशन 5.75 फीसदी

स्वेंस्का के निदेशक:
कारमेन फर्नांडीज द पेरेज—अध्यक्ष
वर्जिनिया कवर द रोड्रिग्स—उपाध्यक्ष
मार्सेला रांगेल द सूमिएंतो—सचिव

कंपनी का प्रबंध देखने वाले:
मार्सेला रोजास द पेरेज

कंपनी के रजिस्ट्रेशन ऑफिस में खातों से संबंधित कोई बयान नहीं

कंपनी मुख्यतः इस पते से काम करती है:
2, रु डू ला कन्फेडरेशन, जेनेवा
(स्विस बैंक कार्पोरेशन का पता)

करार 1986 में समेटा गया. बोफोर्स ने 27.2.86 से 18.12.86 के बीच 18.84 करोड़ क्रोना का भुगतान किया

8.1 करोड़ क्रोना (16.2 करोड़ रुपए)

मोइनियो एस.ए.
लुसाने में पंजीकृत
द्वारा, बर्नार्ड निकोड एस.ए.

सामान्य परामर्श समझौता, 1979
बिक्री पर कमीशन 3 फीसदी
गुप्त नाम: पिटको/मोरेस्को

मोइनियो के निदेशक:
विली मॉक—अध्यक्ष
क्लॉड ब्लैशेट—सचिव
मॉरिस ब्लाइयर्ड—प्रशासन

पुराना निदेशक मंडल:
जे.पी. एस्विनो
एम.बिरस
एम. एस्त्रीबी

करार 1986 में समेटा गया
बोफोर्स द्वारा भुगतान:
- 22.5.86 से 22.12.86 के बीच 3.7 करोड़ क्रोना जेनेवा के मैन्युफैक्चरर्स हनोवर ट्रस्ट के नाम से
- 21.5.86 को 1.2 करोड़ क्रोना क्रेडिट सुइस के नाम गुप्त नाम: मॉट ब्लैक
- 13.11.86 से 22.12.86 के बीच 3.2 करोड़ क्रोना स्विस बैंक कार्पोरेशन के नाम गुप्त नाम: लोटस

5.0 करोड़ क्रोना (10 करोड़ रु.)

ए.ई. सर्विसेज लि.
(पुराना नाम: टार्गेट प्रैक्टिस लि.)
139, हाई स्ट्रीट गिल्डफोर्ड
सरे, इंग्लैंड

बोफोर्स का प्रतिनिधित्व
भारत और दूसरे देशों में करने
का करार 1985 में. करार में
"सावधानी से तैयार की गई
गुप्त शर्तें" भी शामिल
बिक्री पर कमीशन 3 फीसदी

प्रवर्तक: मेजर आर.ए. विल्सन (रिटायर्ड)
निदेशक: मांइल्स टीडेल स्टॉट,
रीता जुबुनेन

नियंत्री कंपनी: सीआऊ एंस्टाल्ट
वाडुज लिस्टेस्टिन
(सीआऊ: कंसोर्टियम फॉर इन्फार्मेशन
एसिमिलेशन ऐंड आउटपुट यूनिट)

बदले में नियंत्रण:
डिवीजन बेनिफिशियरीज एकेडिटियर्स लि.
1501 हचिसन हाउस
हांगकांग

करार 5.3.86 को समेटा गया
बोफोर्स ने 11.9.86 को
5.0 करोड़ क्रोना का भुगतान
नोर्दफिनांज बैंक में किया

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दागने की क्षमता बेहतर है. सुंदरजी ने कहा कि इस क्षमता पर जोर देना इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि भारत के पड़ोसी देशों ने नई रडार तकनीक हासिल कर ली थी.

फ्रांसीसी और स्वीडिश तोपों के अंतिम तकनीकी मूल्यांकन में दोनों की खूबियां और खामियां पाई गई थीं. लिहाजा, दोनों में से किसी को भी स्पष्ट वरीयता नहीं दी गई. फ्रांसीसी तोप का जमीनी संचालन बेहतर था, जमीन पर उसकी छाया छोटी बनती थी, उसमें गोला भरने और दागने की सुविधाएं बेहतर थीं, उसके गोलों की पहुंच बेहतर थी, खराब होने की संभावनाएं कम थीं और उसकी मार भी काफी बेहतर (बोफोर्स के

मोहन कात्रे | एस.के. भटनागर | आर. गणपति | के. सुंदरजी

220 के मुकाबले 500 किमी) थी.

लेकिन बोफोर्स तोप की विशेषता यह थी कि वह फ्रांसीसी तोप के मुकाबले कम जगह में ही चक्कर काट सकती थी. इसके चालक दल में छह सदस्य थे (जबकि सोफ्मा के चालक दल में सात थे). थका हुआ चालक दल बोफोर्स तोप को आसानी से चला सकता था. गोला दागने की उसकी क्षमता भी बेहतर थी. जाहिर है, दोनों तोपों में से किसी एक को चुनना मुश्किल था. लेकिन तथ्य यह है कि अंतिम फैसला करने से दो महीने पहले तक सेना को फ्रांसीसी तोपें ही ज्यादा पसंद थीं. लेकिन फरवरी 1986 में मामला उलट गया. अंतिम मूल्यांकन रिपोर्ट में फ्रांसीसी तोपों की खूबियों को कम करके स्वीडिश तोपों की विशेषताओं को महत्वपूर्ण बताया गया.

इस तरह, बोफोर्स की गोला दागने की बेहतर क्षमता का ब्यौरा तो दिया गया लेकिन ज्यादा दूर तक मार करने की फ्रांसीसी तोपों की विशेषता को नजरंदाज कर दिया गया. गोला दागने की क्षमता के निर्णायक पहलू के बारे में शर्त यह थी कि तोप 15 से 20 सेकेंड के भीतर तीन चक्र गोला दागे. बोफोर्स तो 13.5 सेकेंड में तीन चक्र गोला दागने में सफल रही जबकि सोफ्मा को 15 सेकेंड लगे.

जहां तक कीमत का सवाल है, समिति का कहना है कि फ्रांसीसी तोपों के मुकाबले बोफोर्स तोपें सस्ती थीं. लेकिन समिति ने इस बारे में अपनी रिपोर्ट में जो तथ्य दिए हैं वे गोलमोल ही हैं. रिपोर्ट में कहा गया है, "यदि छूट के बाद की मौजूदा कीमतों (कर्ज की शर्तों, 15 साल में की जाने वाली अदायगी आदि की शर्तों के मद्देनजर) को देखा जाए तो बोफोर्स तोपें कुछ महंगी ही पड़ेंगी." लेकिन इसके तुरंत बाद यह भी कहा गया है कि "यह कोई भारी अंतर नहीं है."

दरअसल, कीमतों का अंतर था भी बहुत कम. 11 मार्च 1986 को बोफोर्स का सौदा 54 करोड़ रुपए सस्ता था. लेकिन जिस दिन 21 मार्च 1986 को सौदे की अंतिम पेशकश हुई, (मुद्रा की कीमतों में परिवर्तन के कारण भी) बोफोर्स की 1,140.3 करोड़ रुपए के सौदे की पेशकश फ्रांसीसी पेशकश (1,126.4 करोड़ रुपए) से 14 करोड़ रुपए अधिक थी. फ्रांसीसी कंपनी कर्ज की बेहतर शर्तें भी रख रही थी. फिर भी तत्कालीन सचिव (व्यय) आर. गणपति ने समिति के सामने बयान दिया कि "वित्तीय रूप से बोफोर्स की पेशकश सस्ती थी." समिति ने बोफोर्स तोपों में चालक दल के सदस्यों की कम संख्या और भावी मूल्य वृद्धि की आसान शर्तों का जिक्र करते हुए गणपति की बातें मान लीं. अन्नाद्रमुक सांसद अरुणा ने कहा है कि सोफ्मा कंपनी कीमत न बढ़ाने पर सहमत थी.

समिति ने वस्तुतः बोफोर्स, उसके अधिकारियों और भारत में उसके प्रतिनिधि विन चड्ढा के हर दावे को मंजूर कर लिया और स्वीडन में इसी मामले की जांच कर रहे लोगों से संपर्क साधने की कोई कोशिश नहीं की. समिति की सहायता करने वाली भारतीय जांच एजेंसियां तो उतने तथ्य भी नहीं जुटा पाईं जितने पत्रकारों ने जुटा लिए. बोफोर्स द्वारा किए गए भुगतानों के संदर्भ में उद्धृत 'क्रेडिट सुइस' के किन्हीं ली फोंड का पता तक सीबीआई नहीं लगा पाई.

भुगतान वाले मामले में भारतीय एजेंसियां ए.ई. सर्विसेज के रिटायर्ड मेजर आर.ए. विल्सन से ही संपर्क साध पाईं. (सीबीआई निदेशक मोहन कात्रे इन जांच एजेंसियों का समन्वय कर रहे थे). और ये विल्सन महोदय बोफोर्स के साथ अपनी कंपनी के सौदे के बारे में सिर्फ चर्चा करने के ही इच्छुक नहीं थे बल्कि उन्होंने करार समेटने संबंधी दस्तावेज भी दिखा दिया. और अंत में यह प्रमाणपत्र भी जारी कर दिया कि सौदे में कोई भी भारतीय शामिल नहीं था.

समस्या का एक पहलू यह भी है कि समिति ने मुख्यतः उन्हीं लोगों से बातचीत की जो फैसले लेने वालों में शामिल रहे, चाहे वे सरकार के लोग हों या बोफोर्स कंपनी के. स्वतंत्र रूप से जांच करने या फाइलें देखने की जहमत तक नहीं उठाई गई ताकि सरकारी नजरिये से अलग भी कोई बात उजागर हो सके. समिति ने ऐसा ही रास्ता अख्तियार कर लिया जिसमें स्वतंत्र रूप से सोचने और काम करने की जरूरत ही नहीं थी.

समिति का तर्क यह हो सकता है कि सरकार ने दोनों कंपनियों से कड़ा मोल-भाव किया जिससे आखिरी दो महीने में उनकी बोली लगभग 200 करोड़ रुपए घट गई. बोफोर्स ने अपने एजेंटों से करार किया था कि सरकार के कहने पर वह उनकी सेवाएं खत्म कर देगी, इस तथ्य से भी करार समेटने के लिए उन्हें भुगतान किए जाने के दावे को थोड़ा बल मिलता है.

फिर भी, कई अहम सवाल अनुत्तरित रह गए हैं. ये सवाल रक्षा सचिव एस.के. भटनागर ने बोफोर्स कंपनी को 16 जून 1987 को भेजे थे. बोफोर्स से पूछा गया था कि जिन कंपनियों के नाम भुगतान किए गए उनके पीछे कौन लोग हैं, और फिर उन्हें भुगतान किन सेवाओं के लिए किया गया. अरुणा ने अपनी असहमति टिप्पणी में लिखा है, "रिपोर्ट के निष्कर्षों में सौदे के तथ्यों को छिपाया गया है और दलाली खाने वालों के नाम बताने से इनकार किया गया है."

उधर नोबेल उद्योग समूह के अध्यक्ष ने कबूल किया है कि बोफोर्स द्वारा किया गया भुगतान रिश्वत हो सकता है. स्वीडिश संसद की संविधान समिति ने तो सौदे में गांधी परिवार के शामिल होने तक की बात कही है.

पिछले पखवाड़े एचडीडब्ल्यू पनडुब्बियों की जांच रुकवा दी गई. जांच का आदेश तत्कालीन रक्षामंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने पिछले साल अप्रैल में दिया था. रक्षामंत्री कृष्णचंद्र पंत ने संसद में घोषणा की कि इन पनडुब्बियों के सौदे में कोई दलाली नहीं दी गई थी. लेकिन सौदे से संबंधित दस्तावेजों में दलाली का साफ जिक्र है. लेकिन जहां तक बोफोर्स घोटाले का सवाल है, इसमें शक नहीं कि अभी इसका पटाक्षेप नहीं हुआ है.

—टी.एन. नाइनन और प्रभु चावला

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

धमाकेदार दस्तावेज

बोफोर्स सौदे से हिंदुजा घराने का रहस्यमय रिश्ता उजागर

बोफोर्स घोटाले का पर्दाफाश करने के लिए समाचार माध्यम सरकार से लगातार जूझते रहे हैं पिछले पखवाड़े मद्रास मुख्यालय वाले दैनिक 'द हिंदू' ने धमाकेदार दस्तावेज छाप-कर दूसरों से बाजी मार ली.

'द हिंदू' ने पांच दस्तावेजों की फेसीमाइल कापियां छापीं. इनमें से दो दस्तावेज तोप सौदे से विवादास्पद हिंदुजा व्यापारिक घराने के संबंध स्थापित करते हैं. ये ताजा रहस्यो-द्घाटन संयुक्त संसदीय समिति की जांच रिपोर्ट की कलई खोलते हैं.

ये दस्तावेज बोफोर्स द्वारा 1982 में स्वेरिजेस रिक्सबैंक (स्वीडन के केंद्रीय बैंक) को भेजे गए आवेदन थे. इनमें 'पिटको' को भुगतान करने का अनुरोध किया गया था. 'पिटको' का पता एक बार 'मार्फत संम लिमिटेड, न्यूजीलैंड हाउस, हाकॅर्ट, लंदन' और दूसरी बार 'मार्फत जी.पी. हिंदुजा, संगम लिमिटेड...' लिखा गया है.

दो और दस्तावेज (अक्तूबर 1979 तक के) भारत से हुए तिरपन सौदों पर 10 फीसदी दलाली दिए जाने को लेकर बोफोर्स और 'पिटको' के बीच हुए करारों के बारे में हैं. बाद में दलाली की यह रकम घटाकर 8 फीसदी कर दी गई. अंतिम दस्तावेज 30 जून 1984 का है जिसमें कहा गया है कि पिटकों से हुआ करार अब 'मेसर्स मोरेस्को' को हस्तांतरित किया जाता है.

हिंदुजा बंधुओं ने तुरंत कहा कि ये दस्ता-वेज पूरी तरह फर्जी हैं. लेकिन उन्होंने इस मामले में मुकदमा दायर करने की धमकी नहीं दी. 'द हिंदू' के सहयोगी संपादक एन. राम ने कहा कि गोपीचंद हिंदुजा उनके संपर्क में रहे हैं. मजेदार बात यह है कि इस प्रकरण से जुड़ी बोफोर्स कंपनी और स्वीडिश बैंक ने इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता से इनकार नहीं किया. लेकिन गोपीचंद हिंदुजा द्वारा 'इंडिया टुडे' को टेलीफैक्स से भेजे दस्तावेजों के मुताबिक उनके वकीलों ने बोफोर्स कंपनी के साफ-साफ बयान देने का आग्रह किया कि 'द हिंदू' अखबार द्वारा प्रकाशित दस्तावेज जाली हैं. इसके लिखित जवाब में बोफोर्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष पेर ओव मोरबर्ग ने दस्तावेजों की प्रामाणिकता से संबंधित सवाल की तो अनदेखी कर दी लेकिन इतना जरूर कहा कि उनकी कंपनी का हिंदुजा की किसी कंपनी से लेना-देना नहीं.

पहला 'गोला' दागने के तुरंत बाद 'द हिंदू' ने दूसरा गोला भी दागा. इस बार उसने बोफोर्स और 'मोइनियो' (पिटको और 'मोरेस्को'—ये सांकेतिक नाम इसी स्वीडिश कंपनी के लिए इस्तेमाल किए गए) के बीच दलाली की रकम को लेकर हुए दूसरे करार की कॉपी छापी. इस नए करार में बोफोर्स सौदे में दलाली के लिए हुआ पहला करार रद्द किया गया था और रद्द करने की फीस के रूप में 8 करोड़ क्रोना (16 करोड़ रु.) देने की बात कही गई थी. यह रकम 1986 में किस्तों में अदा की जानी थी. यदि इस करार पर अमल हुआ है तो बोफोर्स ने 'मोइनियो' को 1986 में 8.1 करोड़ क्रोना दिए हैं.

'द हिंदू' के इस भंडाफोड का सारा श्रेय उसकी जेनवा संवाददाता चित्रा सुब्रमण्यम को जाता है. वे तकरीबन साल भर पूरे समय बोफोर्स घोटाले की तह तक पहुंचने की कोशिश करती रहीं. इस खोजी अभियान को मद्रास से संचालित करने वाले एन. राम ने हेलसिंकी में बसे अपने समाजशास्त्री मित्र वी.के. रामचंद्रन की भी मदद ली.

जहां तक हिंदुजा का सवाल है तो ताजा रहस्योद्घाटन के बाद तमाम निगाहें उन पर केंद्रित हो गई हैं. संगम लिमिटेड (जिसका नाम 'द हिंदू' में छपे दस्तावेजों में आया है) लंदन में उनकी मुख्य कंपनी है जिसका पंजीकरण 1964 में हुआ था. कंपनी की शेयर पूंजी सिर्फ 5,000 पाउंड (एक लाख रु.) थी और एक पाउंड को छोड़कर बाकी पूरे शेयर चार भाइयों में तीसरे—प्रकाश हिंदुजा—के नाम थे. वे स्विट्जरलैंड में रहते हैं पर पता तेहरान का लिखवाया गया है.

कंपनी का सालाना कारोबार 1983 में 304, 589 पाउंड (61 लाख रु.) था. कहा

चित्रा सुब्रमण्यम
जेनेवा में

'द हिंदू' ने बोफोर्स तोप सौदे से संबंधित जो दस्तावेज छापे उनसे संयुक्त संसदीय समिति की जांच रिपोर्ट की कलई खुल गई. सरकार बगलें झांकती नजर आई

एन. राम
मद्रास में

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. Varanasi

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गया है कि यह पूरी आमदनी मध्यपूर्व में एजेंसी कमीशन (दलाली) के रूप में अर्जित की गई. इसमें कर-पूर्व लाभ 14,835 पाउंड (तीन लाख रु.) है.

'द हिंदू' में प्रकाशित दस्तावेजों के अनुसार स्विट्जरलैंड में इस घोटाले से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कोई 'मार्शी' है. लगता है ये 'मि. मार्शी' ब्रिटिश बैंक ऑफ द मिडिल ईस्ट, कांटिनेंटल इलिनोइस बैंक और खुद 'मोरेस्को' की तरफ से इस घोटाले से जुड़े हैं. 'द हिंदू' में छपे पांच में से तीन दस्तावेज मार्शी को संबोधित करके लिखे हुए हैं. स्विडिश अखबार 'एक्सप्रेसन' द्वारा प्रकाशित खबरों में भी एमिल मार्शी नामक व्यक्ति का जिक्र है जो जेनेवा के मैन्यूफैक्चरर्स हनोवर ट्रस्ट से जुड़ा है.

इस दफ्तर में मार्शी से फोन से संपर्क करने पर ऐसा लगा कि उन्हें भारत में उठे विवाद

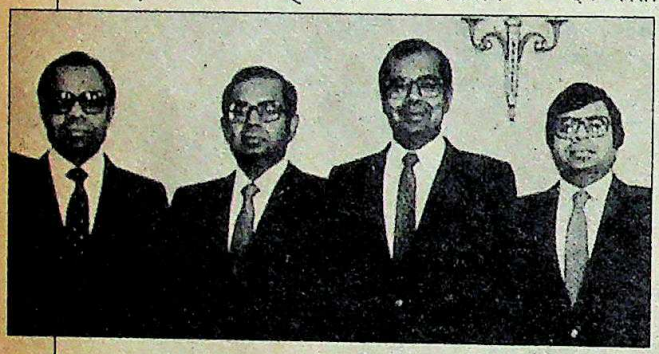

हिंदुजा बंधुः आरोपों का खंडन

में खुद के शामिल होने के बारे में कुछ पता ही नहीं है. उनसे पूछा गया कि क्या वे जानते हैं कि भारत सरकार बोफोर्स तोपें खरीदने जा रही है? उन्होंने कहा, "हां, वे जो भी खरीदना चाहें, खरीद सकते हैं." लेकिन उन्हें जब बताया गया कि प्रकाशित दस्तावेजों में उनका भी जिक्र आया है और इन दस्तावेजों से तोप सौदे में दलाली दिए जाने का संकेत मिलता है, तो वे अचंभे में पड़ गए. उन्होंने कहा, "एकदम बकवास. मैं इन दस्तावेजों को देखना चाहता हूं क्योंकि मैं जिम्मेवार लोगों पर मुकदमा चलाना चाहूंगा." पर उन्होंने इस सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया कि क्या वे पहले ब्रिटिश बैंक ऑफ मिडिल ईस्ट के लिए काम कर चुके हैं?

इस बीच सरकारी जांच करने वालों ने 'द हिंदू' में प्रकाशित दस्तावेजों में कुछ खामियां ढूंढ़ी हैं. जिन विसंगतियों की ओर इशारा किया जा रहा है, वे हैं:

► यह सर्वविदित है कि बोफोर्स के भुगतान की रकम एक बैंक से दूसरे में भेजी गई लेकिन रिक्सबैंक के आवेदन में सिर्फ भेजने वाले बैंक का जिक्र है. जो बैंक 'पिटको' के नाम से रकम लेता था, उसका जिक्र नहीं है.

► भुगतान वाले आवेदन 1982 के हैं; इसलिए 1986 में हुए बोफोर्स के भुगतान में ये कैसे प्रासंगिक हो जाएंगे?

► बोफोर्स और 'पिटको' के बीच हुए करार का सारा ब्यौरा एक बैंक अधिकारी को क्यों बताया जाता. यहां तो सिर्फ बैंक को एकाउंट नंबर बताकर उसमें रकम जमा कर लेने का निर्देश देना ही काफी था.

लेकिन स्वीडन स्थित 'इंडिया टुडे' के सूत्रों के अनुसार ऐसे दस्तावेजों में पैसा जमा होने वाले बैंक का नाम बताना हर बार जरूरी नहीं होता. सौदे के लिए एक दशक पहले ही बातचीत शुरू हो गई थी इसलिए 1982 में भुगतान अप्रासंगिक नहीं है.

इन दस्तावेजों की पुष्टि का काम सिर्फ सरकार ही करा सकती थी. लेकिन वह एकदम निष्क्रिय बैठी रही. प्रधानमंत्री ने मद्रास में कहा कि इस मामले की जांच का जिम्मा संयुक्त संसदीय समिति का है. केंद्रीय जांच ब्यूरो के एक बड़े अधिकारी से जब पूछा गया कि क्या उनका संगठन जांच कर रहा है तो उनका जवाब था कि संसदीय समिति के कहने पर ब्यूरो जांच कर सकता है. लेकिन संसदीय समिति ने भी अपना कामकाज जल्दी-जल्दी समेट लिया, 'द हिंदू' के रहस्योद्घाटन पर ध्यान नहीं दिया और तय समय से पहले ही रिपोर्ट संसद को सौंप दी. राम बताते हैं कि अगर सरकार अधिकृत रूप से यह घोषणा करे कि उसे दस्तावेजों की सचाई पर भरोसा नहीं है, तो दस्तावेज अधिकृत हैं या नहीं यह जानने के लिए स्वीडन में फौजदारी जांच शुरू हो सकती है.

'इंडिया टुडे' को पता चला है कि ऊपरी सरकारी अकर्मण्यता के बीच इस नए हमले से बचाव की नई रणनीति तैयार करने में कई लोग गुपचुप तौर पर लगे हुए हैं. बचाव का पुराना किला तो इस नए हमले से ध्वस्त हो चुका है. इस बीच अखबारी प्रतिद्वंद्विता में 'द हिंदू' का मुकाबला करने वाला 'इंडियन एक्सप्रेस' भी एक बार फिर बोफोर्स प्रकरण को जोर-शोर से उठाने की तैयार में लगा है. इसके संपादक अरुण शौरी एक बार फिर स्वीडन जा पहुंचे हैं. 'हिंदू' भी नए रहस्योद्घाटन की तैयारी में है. ऐसे में लगता है कि बोफोर्स मामले में अभी जोर के धमाके होते रहेंगे.

—टी.एन. नाइनन
और स्टॉकहोम से हैकन राइलैंडर

विन चड्ढा

'मैं तो कुछ भी नहीं जानता'

बातूनी और उग्र स्वभाव वाले व्यवसायी विश्वेश्वरनाथ चड्ढा को कई शिकायतें हैं, खासकर अखबारों और राजनीतिकों से. बातचीत के दौरान वे अखबारों की कतरनें दिखाने का एक भी मौका नहीं चूके. उनका मानना था कि ये खबरें उन्हें बदनाम करने की मंशा से लिखी गई हैं. उनके पास ऐसी कम-से-कम 30 किलो कतरनें जमा हो चुकी हैं.

साल भर बाद अमेरिका से लौटे बोफोर्स के इस प्रशासनिक सलाहकार ने संयुक्त संसदीय समिति द्वारा पिछले पखवाड़े रिपोर्ट पेश करने के लगभग तुरंत बाद ही अपना पहला इंटरव्यू 'इंडिया टुडे' को दिया. तीन घंटे की बातचीत में उनकी उम्र के बारे में पूछे गए सवाल समेत कई के जवाब देने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया. बोफोर्स के बारे में तो वे हर सवाल से बचने की कोशिश करते रहे. बातचीत के अंशः

● ***यह संयोग ही लगता है कि जब बोफोर्स घोटाला उछला तब आप अमेरिका में थे.***

मैं पिछले साल 3 मई को व्यवसाय के सिलसिले में अमेरिका गया. मैंने रिजर्व बैंक से विदेशी मुद्रा ली थी और नियमित तरीके से ही टिकट खरीदा. मैं चुपचाप, बिना किसी को कुछ बताए रात के अंधियारे में नहीं खिसक लिया.

● ***कितने दिन रुकने का इरादा था?***

दो से तीन हफ्ते तक. मैं गया तो था व्यावसायिक कारणों से पर वहां जाकर बीमार पड़ गया. बीमारी बढ़ गई तो मेरे रिश्तेदारों ने कहा कि इस हालत में आपको नहीं जाने देंगे.

● ***आपकी पहली डॉक्टरी जांच कब हुई?***

मई में ही. और उसके बाद तो हालत लगातार बिगड़ती ही गई क्योंकि भारत सरकार मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही थी. वहां मैं बीमार था और यहां सरकार ने मेरे खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी.

● ***तो आप बिस्तर पर पड़े थे?***

बिलकुल. मेरी हालत बहुत खराब थी.

● ***आपकी पत्नी और बेटे कहां थे?***

पत्नी, बेटा, पतोहू, पोते-पोती सभी वहीं थे. मेरी पत्नी पहले ही वहां पहुंच गई थी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

क्योंकि उसे मेरी बीमारी की खबर दे दी गई थी. फिर एक दिन अचानक मेरे भाई ने मेरे बेटे को फोन करके कहा कि तुम्हारे पिता मृत्युशैया पर पड़े हैं. फौरन यहां चले आओ. इसलिए वह भी वहां पहुंच गया.

● ***क्या सच में दिल का दौरा पड़ा था?***

हां, मुझे दिल का दौरा पड़ा था.

● ***क्या आप अस्पताल में भर्ती हुए?***

हां, समय-समय पर.

● ***किस अस्पताल में?***

कई अस्पतालों में. मैं अपने इलाज की कहानी नहीं कहना चाहता. डॉक्टरी जांच से साबित होता है कि मैं बीमार था.

● ***आपके यहां से जाने के वक्त पर भी अफवाहियां उठाई जाती हैं.***

बोफोर्स का मामला 16 अप्रैल से शुरू हुआ. मैं पूरे अप्रैल नहीं था. पर जयपाल रेड्डी (जनता सांसद) ने अप्रैल में ही कहना शुरू कर दिया कि मैं देश से भाग गया हूं. मैंने उन्हें फोन किया और बताया कि मैं यहीं हूं. आप आकर मुझसे बात कर सकते हैं. उन्होंने कहा, मुझे अफसोस है कि मैंने गलत बयान दे डाला. मैंने कहा, आपने बयान दे दिया तो अब उसे वापस ले लीजिए. उन्होंने वायदा किया कि वे बयान वापस ले लेंगे पर नहीं लिया.

● ***क्या आपको बोफोर्स का प्रतिनिधि होने के नाते यहीं नहीं रहना चाहिए था?***

मेरा जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है या बोफोर्स का कारोबार?

● ***मगर जाने से पहले आपको नहीं लगा कि ऐसे समय आपको चाहिए कि...?***

मेरे दूसरे धंधे भी हैं. मैं बोफोर्स का कर्मचारी नहीं हूं. मैं स्वतंत्र व्यवसायी हूं. मुझे कहां जाना है, क्या करना है इसका फैसला मैं खुद करता हूं.

● ***लेकिन बोफोर्स आपकी सबसे बड़ी आसामी थी?***

आप 'सबसे बड़ी' कैसे कहते हैं? मुझे अपने धंधे के बारे में बताने की जरूरत नहीं है. पर अकेला यही (बोफोर्स) मेरा धंधा नहीं है. दूसरों से मैं बहुत पैसा कमाता हूं.

● ***अब लौटने का फैसला क्यों किया?***

डॉक्टर का तो कहना था कि मैं और 90 दिनों तक सफर न करूं. पर मैं पूरी तरह चलने-फिरने के काबिल हो चुका था. मेरे रिश्तेदारों ने, जो डॉक्टर भी हैं, कहा कि यदि आप उत्तेजित न हों तो थोड़े समय के लिए भारत जा सकते हैं. फिर एक दिन सुबह मुझे संदेश मिला कि भारतीय महावाणिज्य-दूत की एक चिट्ठी आई है. उस चिट्ठी में शंकरानंद की ओर से आग्रह किया गया था कि संयुक्त संसदीय समिति मुझसे 7 और 8 अप्रैल को मिलना चाहती है.

● ***चिट्ठी आप तक कैसे पहुंची?***

मेरे डॉक्टर और वकील की मार्फत. उसके तुरंत बाद मैंने महावाणिज्यदूत को फोन करके कहा कि भारत जाने के लिए तो मुझे पासपोर्ट चाहिए. उन्होंने कहा कि हम आपको यात्रा के दस्तावेज दे देंगे. मैंने कहा कि मैं यात्रा-दस्तावेज नहीं, पासपोर्ट चाहता हूं.

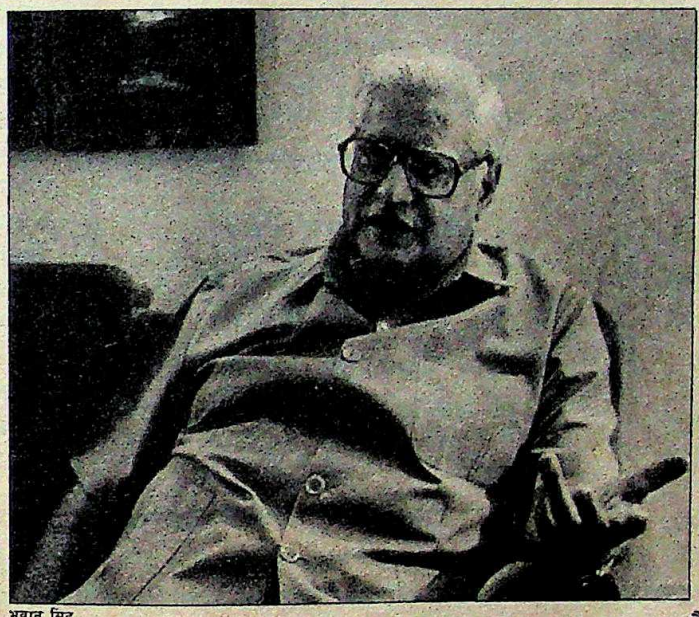

भवान सिंह

बोफोर्स से मेरा संबंध एक खुली किताब के समान है. मेरी जानकारी के अनुसार बोफोर्स के किसी प्रतिनिधि ने नहीं कहा कि दलाली दी गई

उन्होंने पूछा—क्यों. मैंने कहा, मैं बीमार हूं और मुझे अपनी हालत ठीक नहीं लगी तो मुझे बीच में कहीं एक-दो दिन रुकना पड़ेगा. इसलिए आपको मुझे पासपोर्ट देना होगा.

यह जो कुछ अखबारों-पत्रिकाओं में छपा है कि चड्ढा ने सरकार से सौदा किया, शर्तें रखीं और सरकार ने उनकी शर्तें मान लीं, सब बकवास है.

● ***तो आपने संसदीय समिति की वजह से भारत लौटने का फैसला किया?***

मैं सोचता रहा कि मुझे लौटना चाहिए या नहीं. फिर मैंने सोचा कि अब मैं ठीकठाक हूं. मुझे यह भी लगा कि जब तक मैं लौटूंगा नहीं, सरकार से लड़ूंगा नहीं तब तक मैं अपने बैंक खातों पर से पाबंदी नहीं हटा पाऊंगा.

एक और झूठी खबर फैलाई गई कि मैंने अपने खातों पर से पाबंदी हटवा ली है (आवाज ऊंची करते हुए) मेरे खातों पर आज भी पाबंदी लगी है.

● ***आपके सभी खातों में से किसी पर से पाबंदी नहीं हटी?***

मेरे बेटे के खाते को छोड़कर. इसी खाते से मुझे अपने टिकट और विनिमय मुद्रा के लिए पैसा निकालने की इजाजत मिली. जिस तरह की कड़ाई मेरे प्रति, मेरे परिवार तथा मेरी कंपनियों के प्रति बरती गई वह कल्पना से परे है. उन लोगों ने मेरे खिलाफ सम्मन जारी करने शुरू किए. उसके बाद कहा गया कि सम्मन लिए नहीं जा रहे हैं. किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि इसकी वजह क्या है.

● ***सरकार जानती थी कि आप कहां हैं?***

सरकार को परवाह ही नहीं थी. वे नहीं जानते थे. वे जान भी कैसे सकते थे? 'आ बैल, मुझे मार' कहने में मेरा यकीन नहीं है. मेरे कर्मचारियों तक को मेरे बारे में पता नहीं था.

● ***संसदीय समिति के कार्यवाही में कहा गया है कि आपने लौटने के लिए शर्तें रखीं.***

मैंने कोई शर्त नहीं रखी. संसदीय समिति के एक सदस्य ने मुझसे पूछा, क्या आपने शर्तें रखीं? मैंने कहा, नहीं. एक दफा मैंने कहा था कि मेरे बेटे को अमेरिका आने दिया जाए जिससे मैं उसके साथ यात्रा कर सकूं. लेकिन उन्होंने इजाजत नहीं दी.

● ***अमेरिका में भारतीय अधिकारियों के साथ मुलाकातों में आपकी क्या बातें हुईं?***

मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई. सिर्फ एक बार मैं अपना पासपोर्ट लेकर भारतीय दूतावास में अपना मुख्तारनामा प्रमाणित करवाने गया था. उस समय तक चड्ढा को तलाश करने का कोई आदेश नहीं जारी हुआ था. और चड्ढा इतना मूर्ख तो है नहीं कि ऐसी बात जानकर भी दूतावास की तरफ जाता.

● ***आपका पासपोर्ट कब रद्द किया गया?***

मैं कैसे जान सकता हूं? रद्द किए जाने का आदेश आज तक नहीं मिला. अनिल कुमार ने मेरे वकील से कहा कि हम चड्ढा से पूछताछ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

करना चाहते हैं. उन्होंने मेरे दफ्तर में एक संदेश भिजवाया. मेरे डॉक्टर मुझे पूछताछ के लिए जाने देने में ना-नुकुर कर रहे थे पर आखिरकार वे इस शर्त पर राजी हुए कि मुलाकात दो घंटे से ज्यादा नहीं होगी और मुझे सीढ़ियां नहीं चढ़नी होंगी. उस समय मैं हमेशा गोलियां (टैबलेट) साथ लिये रहता था. उसी समय जयपाल रेड्डी ने कहा था कि हर्ष चड्ढा गोवा में है. मैं आग्रह करता हूं कि यदि रेड्डी हर्ष के विदेश जाने और हाल में भारत लौटने के बीच कभी भी उसके भारत में होने की बात साबित कर दें, तो मैं उन्हें एक लाख रुपए दूंगा. और यदि वे ऐसा नहीं कर सकते तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए और संसद से इस्तीफा दे देना चाहिए.

● ***वे (सरकारी अधिकारी) आपसे क्या पूछ रहे थे?***

सवाल पूछने में उन्होंने किसी तरह की कोताही नही बरती. इस बारे में जो कुछ छपा कि यह मुलाकात तयशुदा थी और उसका मकसद लीपापोती करना था, निरा बकवास है.

● ***उन्होंने यह भी पूछा कि क्या कोई भारतीय राजनीतिक भी सौदे में शामिल था?***

नहीं, उन्होंने मुझसे इन कंपनियों के बारे में पूछा. कोई नेता या अफसर इसमें शामिल था या नहीं यह मुझे क्या खाक पता.

● ***असल सवाल यह है कि क्या लोगों ने आपसे यह सवाल पूछा.***

क्या उन लोगों ने मुझे राजीव गांधी को पाक-साफ करार देने को कहा? नहीं. आपके सवाल का मकसद क्या है? वे जानना चाहते थे कि क्या मुझे पता है कि रकम किसने हासिल की? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जानता. राजनीतिक या अधिकारी वाला सवाल ही कहां उठता है? मैं किसी का भोंपू नहीं हूं. जो सच है मैं वही कहता हूं.

● ***सवालों का असली मुद्दा क्या था?***

बोफोर्स. इस बारे में मुझे क्या खाक पता है? मैं तो सलाहकार हूं. वे (बोफोर्स वाले) मेरे पास अपनी समस्याएं लेकर आए थे. उनके साथ हुए करार के मुताबिक मुझे जो सेवाएं देनी चाहिए थीं मैंने उन्हें दी. उनकी कंपनी बड़ी है. हर राज़ अपने हर प्रतिनिधि या सलाहकार को क्यों कर बताने चले? कोई महामूर्ख ही ऐसा करेगा. मेरी हैसियत ही क्या है? क्या मैं निदेशक या अंशधारी हूं?

● ***सरकार ने आपके साथ क्या किया?***

हे भगवान! वह तो दुख की गाथा है. उन्होंने सम्मन जारी किया. सम्मन मेरे यहां के दफ्तर के पते से जारी किया गया जो मुझे कभी नहीं मिल पाया मेरे वफादार कर्मचारियों को पकड़ा, उनके खिलाफ सम्मन जारी किए, उन्हें प्रताड़ित किया. उन्हें गिरफ्तारी की धमकी दी गई. उसके बाद वे नोटिस जारी करवाने के लिए अदालत में गए क्योंकि वे गिरफ्तारी वारंट लेना चाहते थे. मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट भेजना पड़ा, भारतीय दूतावास के डॉक्टर के पास जांच के लिए साढ़े तीन घंटे बिताने पड़े. डॉक्टर ने प्रमाणित किया कि मैं 60 से 90 दिनों तक यात्रा नहीं कर सकता. इससे पहले अमेरिका में सम्मन जारी किए गए. लेकिन वे मुझ तक नहीं पहुंच पाए. इसलिए उन्होंने यहां और अमेरिका के अखबारों में इश्तहार छपवाए. तिस पर भी अखबारों में यह बकवास छपती रही कि चड्ढा की तलाश सिर्फ लीपापोती है. इसे लीपापोती कहते हैं?

● ***क्या वे जानते थे कि आप कहां है?***

बोफोर्स ही मेरा अकेला धंधा नहीं है. और भी व्यवसाय हैं. पर अपने धंधों के बारे में मैं क्यों बतियाऊं? दूसरों से मेरी अच्छी-खासी कमाई हो जाती है

नहीं, मैं उन्हें क्यों पता लगने देता?

● ***पहले आपका वीसा सिर्फ एक साल के लिए ही था?***

अभी यह बात रहने दीजिए. मुझे फिर अमेरिका जाना है.

● ***आपने संसदीय समिति के सामने कहा कि यह व्यावसायिक वीसा है जो पांच साल तक वैध रहता है.***

हां, यह सच है. पर बस, इतना काफी है.

● ***इससे आपका अमेरिका जाना कैसे प्रभावित होता है?***

मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा. मेरे पास 'ग्रीन कार्ड' है या नहीं इसका जवाब यह है कि मेरा 'ग्रीन कार्ड' रद्द नहीं हुआ. मैंने उसे 1985 में सुपुर्द (सरेंडर) कर दिया था.

● ***आपने ग्रीन कार्ड सुपुर्द क्यों किया?***

व्यक्तिगत कारणों से. मैं इस पर भी बात नहीं करूंगा. किसी को मुझसे यह पूछने का अधिकार नहीं है.

● ***बोफोर्स का प्रतिनिधित्व करते रहेंगे?***

हो सकता है मेरा बना रहना उन्हें अच्छा नहीं लगे. पर मैं इसी धंधे में रहूंगा. मैं किस कंपनी का प्रतिनिधि बनूंगा यह सिर्फ मुझ पर ही निर्भर नहीं करता है.

● ***क्या आपको कभी यह नहीं लगता कि यह खराब व्यवसाय है?***

कुछ भी खराब नहीं है. मुझसे खराब तो यह अखबारी दुनिया है.

● ***इसीलिए आपने अखबारवालों को 'बास्टर्ड' (हरामी) और 'अपनी मांओं से वेश्यावृत्ति करवाओ' जैसी गालियां दे डालीं?***

मैंने किसी पेशे या खास तबके के बारे में कभी ऐसा नहीं कहा. मैंने हवाई अड्डे पर उस व्यक्ति के लिए ऐसा कहा जिसने 'मारो हरामी को' कहा था.

● ***आपने कहा कि आप अभी भी बोफोर्स के प्रतिनिधि हैं?***

मैं उनका प्रतिनिधि नहीं, प्रशासकीय सलाहकार हूं, जनवरी 1986 से.

● ***जनवरी 1986 से पहले और बाद के काम में क्या फर्क रहा है?***

अब हमें बहुत सीमित काम करना होता है. पहले यहां का पूरा काम संभालना पड़ा था. मसलन यदि उन लोगों ने कोई तोप जांच-परख के लिए लाई और वे चाहते हैं कि उसे बंबई बंदरगाह से छुड़ाकर सिक्किम भेज दिया जाए और सिक्किम में डॉक्टर समेत उनके रहने-खाने का इंतजाम किया जाए तो यह सब हमें करना पड़ता था. अब यह नहीं करना पड़ता.

● ***अब उनके लिए यह सब काम कौन करता है?***

कोई नहीं. भारत सरकार खुद करती है वही खरीदार है. उन्हें (बोफोर्स को) दूसरों की क्या जरूरत है.

● ***आप उनकी सरकारी अफसरों से मुलाकात का इंतजाम नहीं करते?***

नहीं, हमने यह सब कभी नहीं किया.

● ***पहले भी नहीं?***

बिक्री के लिए सरकार से हुई बातचीत में हम कभी शामिल नहीं हुए.

● ***अब, बोफोर्स से आपके संबंधों के बारे में. आपने कहा कि जनवरी 1986 और उसके बाद आपका काम बदल गया पर आपका मेहनताना वही रहा.***

मैं इस बारे में बात करने को तैयार नहीं हूं. मैंने संसदीय समिति को भी बता दिया था.

● ***आपने कहा है कि आप करार समेटने के भुगतान के बारे में कुछ नहीं जानते?***

हां.

● ***आप जानते थे कि उनके ऐसे एजेंट हैं?***

मैं कंपनी के साथ अपनी सेवाओं के अलावा कुछ नहीं जानता. और मैं उनमें (एजेंटों में) से नहीं हूं.

● ***आपका मतलब है कि आप सौदे की***

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बातचीत के दौरान किसी सरकारी अधिकारी ने नहीं मिले?

ऐसे सवाल न पूछिए. ये सब घेरने वाले सवाल हैं जिनका अब कोई औचित्य नहीं रह गया है. बोफोर्स से मेरा संबंध एक खुली किताब के समान है. मेरी जानकारी के मुताबिक बोफोर्स के किसी प्रतिनिधि ने नहीं कहा कि दलाली दी गई. क्या किसी ने कहा है कि दलाली दी गई?

• बैंक के दस्तावेजों में भी दलाली (कमीशन) शब्द का प्रयोग है.

आपसे किसने कहा? बैंक के दस्तावेज जर्मनी में नहीं हैं. किसी स्वीडिश से पूछिए. 'प्रोविजंस' शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ 'प्रोविजंस (प्रावधान) ही होता है. 'कमीशन' का अर्थ 'कमीशन' नहीं.

64 करोड़ का भुगतान हुआ. बता सकते हैं यह किसे मिला और क्यों?

कोई टिप्पणी नहीं. रकम का नुकसान सूद, कर्ज, जिम्मेवारी निभाने के लिए, यानी कई तरह हो सकता है.

• लेकिन यह बिक्री का प्रतिशत है.

मैं नहीं जानता. आप जाइए और पता कीजिए. मैंने पहले भी कहा है, मुझसे कुछ नहीं निकलेगा. ऐसा कुछ है ही नहीं. लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि आप लोगों के दिमाग में यह बात साफ-साफ बैठ जानी चाहिए कि यह आदमी कुछ नहीं जानता और इसे परेशान किया गया है. इसके प्रति तो कम से लोगों को सहानुभूति दिखानी चाहिए.

• कहा जाता है कि अप्रैल 1986 में अपने 48वें जन्मदिन पर आपने पार्टी दी थी जबकि आपका जन्मदिन जुलाई में पड़ता है.

क्या अपना 60वां जन्मदिन उसी दिन मनाना जरूरी है? इसे पांच दिन पहले भी मनाया जा सकता है.

• तीन महीने पहले?

छह महीने बाद भी.

• यह पार्टी बोफोर्स का सौदा पट जाने के एक महीने बाद दी गई थी.

एक महीने दो दिन बाद. तो क्या? इससे बोफोर्स का क्या लेना-देना है?

• पार्टी स्थल पर एक प्रतीक लगा हुआ था जिसमें लिखा था '60 के विन अभी भी विजय पथ पर' (विन एट 60 स्टिल विनिंग). 'विनिंग' (विजय पथ पर) बोफोर्स सौदे के संबंध में था?

उसका बोफोर्स से क्या संबंध हो सकता है? यह आपकी खामख्याली है, तथ्य नहीं.

• मतलब यह है कि उस दिन आपका जन्मदिन नहीं था.

आपको जो अच्छा लगे, कह सकते हैं. मैं बोफोर्स के बारे में बात नहीं करना चाहता. आप चाहते हैं कि मैं करार गंवा बैठूं?

• असल सवाल यह है कि रकम का भुगतान हुआ...

मैं कुछ नहीं जानता. और यदि आपको पता लगे तो मुझे भी बता दीजिएगा.

• आप कई वर्षों तक बोफोर्स के सलाहकार रहे हैं और बोफोर्स ने भारत में क्या कुछ किया इस बारे आप कुछ नहीं जानते, यह नितांत अविश्वसनीय लगता है.

यह आप पर है विश्वास करें या न करें.

• आपके खिलाफ दायर मुकदमों में क्या हो रहा है?

आज तक कोई 'कारण बताओ' नोटिस नहीं दिया गया. कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई. मुझे कोई भी ऐसी चिट्ठी नहीं मिली जिसमें कहा गया हो कि यह या वह नहीं करना है अथवा आपने इस या उस कानून का उल्लंघन किया है. जो अकेली चिट्ठी मिली वह पिछले हफ्ते ही. इसमें कुछ दस्तावेजों के साथ मुझे प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होने को कहा गया है. अगले हफ्ते मैं पेश हो रहा हूं.

भारत के इस नौजवान प्रधानमंत्री ने कुछ भी गलत नहीं किया. मुझे कोई स्वार्थ नहीं साधना है. वे मुझे सांसद नहीं बनवा देंगे. नेक इरादे उनमें कूट-कूटकर भरे हुए हैं

• तब आपके बैंक खातों पर किस आधार पर पाबंदी लगाई गई?

उन्हीं से पूछिए! मैं हाईकोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया और उनका कहना था कि हम इस पर विचार करेंगे.

विपक्षी दलों ने 'बावेला' मचाकर बहुत नुकसान किया. और सरकार ने खुद को ईमानदार सिद्ध करने के लिए कार्रवाई की.

• खातों पर पाबंदी रहते आप किराया तथा दूसरे भुगतान कैसे कर रहे हैं?

क्योंकि मेरा एक और खाता है जिस पर पाबंदी लगाना वे भूल गए हैं.

• क्या यह अस्वाभाविक नहीं कि वे एक खाते पर पाबंदी लगाना भूल जाएं.

उनसे पूछिए. मेरे सभी खाते एक ही बैंक में हैं. पर एक खाता हमने बहुत पहले खोला था और उसके बारे में भूल गए थे. अब हमने पाया कि वह अभी भी कायम है.

• आपके जीवन को कैसा खतरा है जिसकी चर्चा आपने अदालत में की है.

पीटीआई की खबर थी कि वी.पी. सिंह ने बंगलूर में कहा कि मेरे जीवन को खतरा है. यदि मेरे दुश्मन मेरी जान पर खतरे की बात कर रहे हैं तो मेरे दोस्तों को चिंता होगी ही.

• आप जब कहते हैं कि जुलाई में आपके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं था यानी तब आपके पासपोर्ट को कुछ नहीं किया गया?

मैंने आपके बताया कि मैं नहीं जानता. और यदि मेरा पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था तो क्या मैं...मैं नहीं चाहता कि जिन हालात से मुझे गुजरना पड़ा उनके 10 फीसदी से भी मेरे किसी दुश्मन को कभी गुजरना पड़े. मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं नहीं जानता. क्या आप सोचते हैं कि मैं आपसे कुछ छिपा रहा हूं? नहीं, ऐसा नहीं है.

• बोफोर्स करार पर लौटें. करार के अनुसार आपको बिक्री राशि पर 0.25 प्रतिशत दलाली (कमीशन) मिलनी थी. और आपने संसदीय समिति के सामने जो कहा उसके अनुसार 1986 में बोफोर्स के साथ हुए नए करार के तहत आपको पांच साल तक इसी के आस-पास कुछ रकम मिलती रहेगी.

इससे बहुत अधिक.

• आपका मतलब कम काम करके आपको ज्यादा रकम मिल रही है?

इसमें कोई विरोधाभास नहीं है. क्योंकि वे मेरे साथ हुआ पहले वाला करार रद्द करने में सक्षम थे. वे सरकार से कह सकते थे कि हमने करार रद्द कर दिया है. मेरे पास असली पत्ता था. कोई इतना मूर्ख नहीं है कि जितना देना है उससे अधिक दे देगा. उन्हें मेरे साथ हुए करार के तहत ही चलना पड़ता. उसे रद्द नहीं किया जा सकता था. इसलिए एक नए करार के तहत वे मुझे एक तयशुदा रकम देने लगे. मैंने उनके खेल में ही उन्हें पछाड़ दिया. मैंने कहा कि आप पिछले करार से मुक्त होना चाहते हैं तो मैं कम-से-कम इतना चाहता हूं. इस पर महीनों बात चली. आखिर उन्होंने 'हां' कर दी.

• तो यह कोई पहेली नहीं है जो सरकार बोफोर्स के साथ खेल रही है कि आपने करार रद्द कर दिया. यह गंभीर मामला है.

हां कृपया मुझ पर भरोसा कीजिए. और एक ईमानदार आदमी के रूप में यही पीड़ा मुझे सबसे ज्यादा सालती है. भारत के इस नौजवान प्रधानमंत्री ने कुछ भी गलत नहीं किया है. मैं आपसे पूरी ईमानदारी के साथ कह सकता हूं कि मुझे किसी से स्वार्थ नहीं साधना है. वे मुझे सांसद नहीं बनवा देंगे या आने वाले समय में मुझे लाभ नहीं दिलवाएंगे. नेक इरादे उनमें कूट-कूटकर भरे हैं.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

श्रीनिवास कुमार

कर्नाटक

जन अदालत में

सतत दौरे पर निकले हेगड़े

मुख्यमंत्रित्व के दूसरे दौर की सबसे बड़ी चुनौती से निबटने के लिए रामकृष्ण हेगड़े ने राजधानी से निकलकर जनता में जाने का फैसला कर लिया. पिछले पखवाड़े किए गए इस फैसले के पीछे मकसद पार्टी असंतुष्टों की लोकप्रियता आंकना और इस आधार पर आगे की रणनीति तय करना है. मुख्यमंत्री 3 मई को पार्टी के 139 विधायकों का विश्वास मत पाने की तैयारी जो कर रहे हैं.

मुख्यमंत्री ने दौरे के लिए इलाकों का चुनाव बड़ी सावधानी से किया— मैसूर, जहां वोक्कलिगा जाति का प्रभाव है (असंतुष्ट मंत्री एच.डी. देवगौडा इसी जाति के हैं); दक्षिण कनारा, जो इंका का गढ़ माना जाता है; शिमोगा और चित्रदुर्ग, जहां कुछ असंतुष्ट पार्टी नेताओं का दबदबा है. बहरहाल, दौरे से जाहिर हो गया कि जनता उनके साथ है.

दक्षिण कनारा के होनावर में 23 अप्रैल को भारी भीड़ उन्हें सुनने के लिए चिलचिलाती धूप में भी देर तक उनका इंतजार करती रही. भीड़ देवगौडा समर्थक स्थानीय विधायक एन.एच. गौडा को हूट करती रही. लोगों का मूड देखकर गौडा ने बैठक की समाप्ति पर कहा भी , "मैं हेगड़े का समर्थन करता हूं. केवल हेगड़े ही मेरे नेता हैं."

पार्टी असंतुष्टों पर जबरदस्त छींटाकशी करते हुए हेगड़े ने सालिग्राम की छोटी सभा में कहा, "खतरा कांग्रेस से नहीं है. खतरा तो अपने ही लोगों से है. खतरा कुर्सी की भूख से है." और मंगलूर में उन्होंने कहा, "सत्ता के भूखे ये असंतुष्ट नेता स्वार्थ और महत्वाकांक्षा से प्रेरित हैं."

इस दौरे से फिर सिद्ध हो गया है कि हेगड़े अपने लिए सहानुभूति लहर खड़ी करने में सफल रहे हैं. दौरे की समाप्ति पर आत्मविश्वास से भरे हेगड़े ने कहा, "लोगों के रवैये से बहुत बल मिला है." लेकिन पार्टी की अंदरूनी स्थिति मनोबल बढ़ाने वाली नहीं थी. पार्टी दफ्तर की दीवारों पर हेगड़े समर्थकों और विरोधियों का पोस्टर

राव का जलता पुतला: विरोध का दृश्य

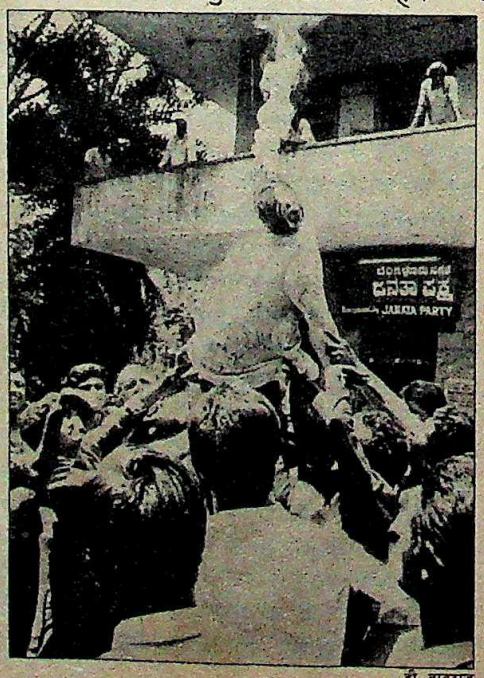

डी. बाबूराज

समर्थकों से मिलते हेगड़े: अभी लोकप्रिय

युद्ध जारी रहा. कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं ने हेगड़े के प्रमुख विरोधी नारायण राव का पुतला जलाया. मुख्यमंत्री ने अब असंतुष्टों पर इंका से सांठगांठ करने का आरोप लगाना शुरू कर दिया है.

मुख्यमंत्री के रूप में हेगड़े का भविष्य अब नई दिल्ली में होने वाले जपा अध्यक्ष के चुनाव पर निर्भर करता है. अगर मधु दंडवते अध्यक्ष बने तो हेगड़े के लिए आसानी हो जाएगी. लेकिन अगर चंद्रशेखर पद छोड़ने पर राजी नहीं हुए तब जनता पार्टी में संकट पैदा हो जाएगा और हेगड़े का भविष्य भी अनिश्चित हो जाएगा.

जो हो, शक्ति परीक्षण तय लगता है. राज्य के पार्टी असंतुष्टों को चंद्रशेखर से शह मिलती रही है जो हेगड़े को राज्य की राजनीति में ही फंसाए रखना चाहते हैं. हेगड़े समर्थक समझौते की कोशिशों के प्रति भी उदासीन रहे उनका कहना है, "चंद्रशेखर विवाद को जिंदा रखना चाहते हैं ताकि 3 मई को हेगड़े कमजोर स्थिति में रहें.

इस बीच असंतुष्ट नेता पिछले पखवाड़े दिल्ली के दौरे से लौट आए. उनकी मांग है, "हेगड़े गद्दी छोड़ें." एन.एम. हुंबरवाडी ने कहा, "हमारा तो यही मानना है कि हेगड़े के गद्दी छोड़ने से ही पार्टी की छवि सुधरेगी." असंतुष्ट नेता 3 मई को गुप्त मतदान के लिए जोर दे रहे हैं. लेकिन हेगड़े ने उनकी मांग ठुकरा दी है. हेगड़े समर्थकों को पूरा भरोसा है कि मुख्यमंत्री बहुमत का विश्वास पाने में सफल रहेंगे.

देवगौडा और दूसरे असंतुष्ट एकजुट होकर भले ही ताकतवर बन गए हों, उनकी नाराजगी के कारण भिन्न हैं. नारायण राव मानते भी हैं, "हमारी समस्या देवगौडा से अलग है." इस पूरे विवाद में तटस्थ रहे एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा, "असंतुष्टों को पार्टी की छवि की चिंता नहीं है. ये लोग राजनैतिक मामले में नौसिखुए ही हैं."

दौरे की सफलता के बावजूद हेगड़े अभी भी परेशान हैं. उन्हें लगता है कि उनकी राष्ट्रीय छवि बिगड़ी है. राज्य जनता पार्टी अध्यक्ष एम.पी. प्रकाश कहते हैं, "आज जो स्थिति है, उसमें उन्हें राज्य की राजनीति छोड़ने नहीं दी जा सकती." शायद यह ठीक भी हो. संभव है वे विधायकों का विश्वास प्राप्त कर लें. लेकिन अपनी राष्ट्रीय छवि का सवाल आगे भी उन्हें परेशान करता रहेगा.

—अनीता प्रताप

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बिहार

इंसाफ का शाही अंदाज

मुख्यमंत्री के दरबार में फरियादें सुनी जाती हैं या ठुकराई जाती हैं

अभी दो महीने पहले तक पटना के 4, किंग जॉर्ज एवेन्यू का आलीशान बंगला राज्य सरकार का अतिथिगृह था. आज इसके लोहे के विशाल फाटक पर खड़े संतरी कोई तलाशी नहीं लेते, किसी तरह के सवाल नहीं पूछते. आने वाले लोग अपने हाथों में फरियाद का कागज थामे अंदर चले आते हैं. तभी लंबी, मजबूत कदकाठी का खादीधारी राजनीतिक एक स्टेनोग्राफर और कुछ अधिकारियों के साथ प्रकट होता है. शामियाने में इकट्ठी बेचैन भीड़ खामोश हो जाती है.

मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद का जनता दरबार लग गया है. यहां इंसाफ 'आजाद शैली' में हाथोहाथ किया जाता है. हर तबके के लोग आजाद के दरबार में आते हैं. कुछ की फरियाद तो हमदर्दी से सुनी जाती है तो कुछ को शाही अंदाज में हाथ के इशारे भर से झिड़क दिया जाता है.

एक मिसाल. 65 वर्षीय एक बुजुर्ग ने शुरुआत की, "श्रीमान, मैं एक स्वतंत्रता सेनानी हूं. मेरा नाम राम प्रसाद गुप्ता है और मैं वैशाली जिले के जरवा बाजार का रहने वाला हूं." आजाद टोकते हैं, "लेकिन आपकी समस्या क्या है?" जवाब दिया जाता है, "कुछ प्रभावशाली लोगों ने मेरी एक सौ आमों के पेड़ वाली जमीन पर कब्जा कर लिया है." आजाद वैशाली के जिलाधीश के लिए एक संक्षिप्त आदेश बोलकर नोट कराते हैं. बुजुर्ग को बता दिया जाता है कि आदेश अगले दिन पहुंच जाएगा.

लेकिन दूसरों की बातें इतनी हमदर्दी से नहीं सुनी जातीं. मसलन वनवासी इंका कार्यकर्ताओं के एक दल ने अपने इलाके में झारखंड आंदोलन के बढ़ते प्रभाव की शिकायत की तो उसे एक लंबा उपदेश पिला दिया गया, "कभी अपने आपसे पूछा है कि ऐसी समस्याएं क्यों हैं? क्योंकि आप लोग काम नहीं करते. गरीबों के प्रति हमदर्द बनिए और काम पूरी निष्ठा से कीजिए."

शामियाने के दूसरी ओर खड़ी महिलाओं की सुनवाई मुख्यमंत्री कहीं बेहतर तरीके से करते हैं. रांची जिले के आरा गांव की एक वनवासी लड़की लूसी एक्का ने वही पुराना दुखड़ा रोया, "गुंडों ने आतंक मचा रखा है. हम उनसे अकेले नहीं लड़ सकते." मुख्यमंत्री कहते हैं, "मैं इसी वक्त जांच का आदेश दे रहा हूं. लेकिन मामला अदालत तक जाएगा और तब आप वहां गवाही तो देंगी न?" लूसी पक्के इरादे वाली लड़की दिखती है, "हां. मैं इसके लिए तैयार हूं."

इसके बाद बारी आई अधेड़ सावित्री देवी की. वे आजाद के पैर छूने लगीं. आजाद गरज पड़ते हैं, "आपसे मेरे पैर छूने के लिए किसने कहा? आपकी कोई समस्या है तो बताइए." वे कहती हैं, "श्रीमान, मैं गया जिले की एक पंचायत की मुखिया हूं. लोग मुझे काम नहीं..." मुख्यमंत्री बीच में टोकते हुए कहते हैं, "क्या? लोग आपको काम नहीं करने देते? कैसी मुखिया हैं आप? जाइए काम कीजिए." ऐसे लोगों के लिए आजाद के पास कोई वक्त नहीं है.

इंका कार्यकर्ताओं का एक दल एक बीडीओ के आदेश पर किए गए लाठीचार्ज की शिकायत करता है. आजाद का चेहरा तमतमा जाता है. वे उन्हें फटकारते हुए कहते हैं, "शर्म की बात है. आपका चरित्र मजबूत होता तो बीडीओ आपका सामना करने की हिम्मत तक न करता." उन्हें बताया जाता है, "बीडीओ भ्रष्ट है. यहां तक कि जिलाधीश की रिपोर्ट भी कहती है कि एक मंत्री उसे संरक्षण दे रहा है." आजाद उसके ऊपर बरस पड़ते हैं, "जबान संभालकर बात कीजिए. मैं आयुक्त को आदेश दे रहा हूं कि जिलाधीश की रिपोर्ट की जांच करके कार्रवाई करें."

इसके बाद आजाद की एक सरकारी अधिकारी से दिलचस्प मुठभेड़ होती है.

अधिकारी, "सर, मुझे बख्श दीजिए."

आजाद, "क्या? सरकारी कर्मचारी होकर आपकी सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचने की हिम्मत कैसे हुई? आप अपने ऊपर के अधिकारी की इजाजत से यहां आए हैं?"

अधिकारी, "नहीं सर, लेकिन..."

आजाद, "इन्हें तुरंत सस्पेंड किया जाए."

अधिकारी, "सर, मुझे बख्श दीजिए..."

आजाद, "ठीक है, इन्हें मुअत्तल मत करो. आप लोग ही अनुशासन तोड़ेंगे तो पूरा सचिवालय ही मुख्यमंत्री के पास चला आएगा क्योंकि इस पृथ्वी पर शायद ही ऐसा कोई शख्स हो जिसकी कोई समस्या न हो."

इसी तरह आजाद का जनता दरबार

कृष्ण मुरारी किशन

दरबार में आए ज्यादातर मामले आम किस्म के ही होते हैं, हालांकि मुख्यमंत्री आजाद ने कह रखा है कि वे ही लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आएं जिनकी कहीं और सुनवाई न हो रही हो

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

चलता है. 23 फरवरी से यह हफ्ते में दो बार लगता रहा है (भागवत झा ने 14 फरवरी को पद भार ग्रहण किया था). हर बार दरबार में बिहार के सभी हिस्सों से लगभग 500 व्यक्ति आते हैं.

ऐसे दरबार कोई पहली बार नहीं लग रहे हैं. इसकी शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र (1980-83) ने की थी जिसे उनके उत्तराधिकारी चंद्रशेखर सिंह (1983-85) ने जारी रखा. बिंदेश्वरी दुबे (1985-88) ने जनता के लिए अपने दरवाजे सदा बंद ही रखे. लेकिन आजाद इन सबसे अलग हैं— मामले के चुनाव में, उसे निबटाने में माहिर और तेज. अधिकारी दावा करते हैं कि दरबार में लिखाए गए उनके आदेश दो दिनों में गंतव्य तक पहुंचा दिए जाते हैं.

आजाद खुद महसूस करते हैं कि दरबार में आए ज्यादातर मामले आम किस्म के ही होते हैं, हालांकि उन्होंने स्पष्ट कह रखा है कि वे ही लोग उनके पास आएं जिनकी मुसीबतों का निवारण और कहीं नहीं हो पा रहा हो. लेकिन कइयों को सचमुच मदद की जरूरत होती है. आजाद कहते हैं, "सबसे महत्वपूर्ण वे लोग हैं जो इंसाफ की तलाश में आते हैं. जैसे अवकाश प्राप्त लोग पेंशन के लिए आते हैं. ऐसे सभी मामलों में मैं चेतावनी के साथ आदेश दे देता हूं."

वास्तव में, ढाई महीने पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद आजाद द्वारा बिहार में चलाए गए स्वच्छता अभियान का एक हिस्सा ही है जनता दरबार. उन्होंने अधिकारियों के जल्दी तबादलों पर रोक लगाई है. भ्रष्ट नौकरशाहों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है. मंत्रियों को आदेश दिया गया है कि वे सचिवालय में सुबह ठीक 10.15 पर हाजिर हो जाएं और शाम को 5 बजे तक अपने दफ्तर में बैठें. आश्चर्य कि ज्यादातर मंत्री इन आदेशों का पालन कर रहे हैं.

लेकिन एक व्यक्ति सबको खुश कर पाए, खासकर बिहार में, यह नामुमकिन है. इसीलिए आजाद के हिस्से में बदनामी भी आई है. उन भ्रष्ट मंत्रियों और नौकरशाहों पर उंगलियां उठाई जाती हैं जो अभी भी पद पर बने हुए हैं. इन आलोचनाओं के प्रति आजाद चिकने घड़े ही साबित होते हैं. लेकिन अपनी उपलब्धियों के आकलन में वे सतर्क दिखते हैं, "मैं दावा नहीं करता कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिखाया है. पर निरुपायता का जो भाव व्याप्त था वह अब खत्म हो चला है." और सचमुच उन्होंने गरीबों की आवाज सुनने में तत्परता दिखाई है.

—फरजंद अहमद

सरकारी विमान

हवाखोरी बंद

इस बात में कोई शक नहीं कि बिहार में बदलाव की हवा बह रही है. वर्षों से राज्य के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और मंत्रियों के अतिथि सरकारी साधनों खासकर सरकारी हवाई जहाज का जी भरकर मुफ्त इस्तेमाल करते थे. पर अब मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद ने सरकारी जहाजों का ऐसा इस्तेमाल रुकवा दिया है. नतीजतन हवाई सफर के आदी नेताओं को परेशानी होने लगी है. पर इससे सरकारी खजाने में इजाफा होने लगा है क्योंकि हर महीने 15 लाख रु. की बचत हो रही है.

अपने मंत्रियों, अधिकारियों और पार्टी के नेताओं को अनुशासित करने के अभियान के तहत ही आजाद ने राज्य सरकार के दोनों जहाजों के दुरुपयोग पर पाबंदी लगा दी है. सचिवालय के सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि राज्य के दोनों जहाजों के उपयोग की इजाजत उनके दफ्तर से लेनी अनिवार्य होगी. एक मंत्री कहते हैं, "आजाद के नेतृत्व में तो सरकारी जहाज से उड़ने की बात सोचना भी 'पाप' है." पर इस नई व्यवस्था का असर दिखने लगा है. हवाई अड्डे के स्रोतों के अनुसार सरकारी जहाजों की उड़ानों की संख्या में 60 से 70 फीसदी तक कमी आ गई है.

आजाद के ढाई महीनों के शासनकाल में ही नियम अब इतने कठोर हो गए हैं कि कोई भी मंत्री बिना किसी मुकम्मल वजह के सरकारी जहाज मांगने की हिम्मत नहीं कर सकता. खुद मुख्यमंत्री भी जहाज का इस्तेमाल सोच-समझकर करते हैं.

मानव संसाधनमंत्री डॉ. नागेंद्र झा को भी हाल में आजाद की सख्ती से दो-चार होना पड़ा. झा माध्यमिक शिक्षकों के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पूर्णिया जा रहे थे जबकि मुख्यमंत्री रांची में थे. झा का सफर पूरा होने में दस मिनट का ही समय रह गया था कि पायलट को रेडियो संदेश मिला कि मुख्यमंत्री को तुरंत विमान चाहिए. पायलट जहाज को पटना लौटा लाया.

कृष्ण मुरारी किशन

सरकारी विमानः पहुंच के बाहर

वहां उसने झा को उतारा और मुख्यमंत्री को लाने के लिए रांची चला गया.

आजाद के नए नियम केंद्रीय मंत्रियों पर लागू नहीं होते. लेकिन हाल में केंद्रीय कानूनमंत्री बिंदेश्वरी दुबे को भी आजाद की नाखुशी झेलनी पड़ी. उन्होंने पटना से बोकारो जाने के लिए सरकारी जहाज का इस्तेमाल किया. शाम को दुबे ने फिर जहाज के लिए पटना संदेश भेजा लेकिन जब तक जहाज पहुंचे तब तक वे एअरलाइंस की उड़ान पकड़ चुके थे. जब विमान खाली ही पटना लौटा तो आजाद के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा. उन्होंने निर्देश दिया कि आगे से दुबे को इस्तेमाल के लिए जहाज न दिया जाए.

अपने पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री से उन्हें एक और हिसाब, 2.5 लाख रुपए के एक बिल का भुगतान करवाना है. दुबे के मुख्यमंत्रित्व में अक्सर उड़ानों की एक सरकारी संस्था से किराये पर जहाज लिए जाते थे.

एक ओर जहां मुख्यमंत्री और वित्त विभाग पिछली सरकार की बकाया भुगतानों की छंटाई में लगे हैं, राज्य के नेताओं की हवाखोरी के दिन लद चुके लगते हैं.

—फरजंद अहमद

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

महाराष्ट्र

न्यायमूर्ति की निंदा

लेंटिन रिपोर्ट पर भारी हंगामा

अपने अनथक उद्यम के बाद भी निर्भय न्यायाधीश चैन की सांस नहीं ले पाते. बंबई के सरकारी जे.जे. अस्पताल में 14 मरीजों की मौत की जांच करने वाले न्यायाधीश बख्तावर लेंटिन आयोग की

विधायिका और वकीलों के बीच छिड़ी इस जंग में लेंटिन के समर्थन में कई दिग्गज कानूनदां भी मैदान में उतर आए हैं

मुश्किलें जांच की रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार को सौंपने के बाद भी खत्म नहीं हुई हैं.

इस रिपोर्ट से उठे विवाद ने पिछले पखवाड़े विधायिका और वकीलों को आमने-सामने खड़ा कर दिया और लेंटिन के पक्ष में नानी पालकीवाला और राम जेठमलानी जैसे दिग्गज वकील भी मैदान में उतर आए.

इस लड़ाई की शुरुआत विधानसभा में लेंटिन और आयोग के उनके वकीलों नवनीत शाह और जे.पी. देवधर के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाए जाने से हुई. खबर है कि विधानसभा में इस कुशाग्र-बुद्धि न्यायाधीश को "कुंठित, सनकी, भयंकर अनैतिक और अपराधी" तक कहा गया. यह प्रस्ताव लेंटिन की उस प्रतिक्रिया पर आया था जो उन्होंने विधानसभा में दिए गए एक बयान पर की थी. इसके जवाब में पश्चिमी भारत वकील संघ ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें विधायकों से यह प्रस्ताव वापस लेने की अपील की गई थी. पालकीवाला ने घोषणा की कि विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पास होने पर वकील सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे.

तुरंत ही विधानसभा में दूसरा विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव आ गया. यह पालकीवाला, बोबडे और दो दूसरे वकीलों के खिलाफ था. वकील संघ ने फिर बैठक करके पालकीवाला वगैरह का समर्थन किया और साथ ही "विधायकों के व्यवहार की बाबत लोगों के बीच होने वाली चर्चा" को दबाए जाने का विरोध किया. जेठमलानी ने कहा

(बाएं से) पालकीवाला, जेठमलानी, लेंटिन, धोंडगे और सावंत

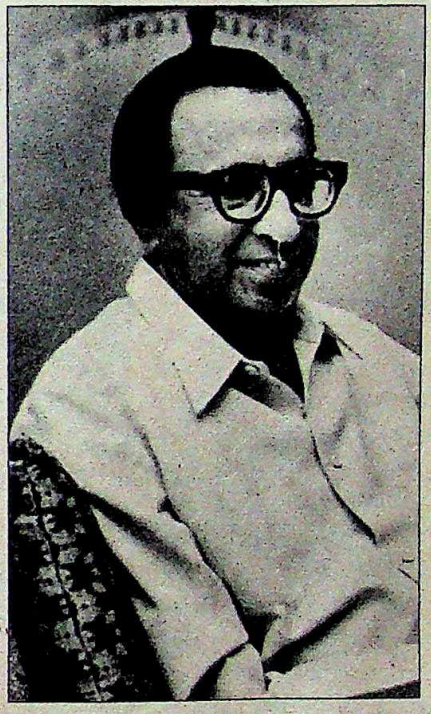

कि 'लेंटिन जैसी ईमानदारी और प्रतिबद्धता की न्यायिक इतिहास में मिसाल नहीं मिलती.' उन्होंने कहा, "इन विधायकों को उनकी औकात बता दी जानी चाहिए." और जैसी उम्मीद थी, जेठमलानी के खिलाफ भी मानहानि का नोटिस आ गया.

आयोग पर होने वाले हमले नए नहीं हैं. साल भर की जांच के दौरान लेंटिन और आयोग के वकीलों को धमकियां और प्रलोभन मिलते रहे. ये बातें इतनी बढ़ गई थीं कि लेंटिन रिपोर्ट का एक पूरा अध्याय ही इस पर लिखा गया है. 'आयोग के कठिन काम' शीर्षक वाले इस अध्याय में लिखा गया है, "स्पष्ट रूप से इस जांच को कुछ लोग पसंद नहीं करते थे. इसी कारण आयोग की बार-बार अवमानना की गई, उसे परेशान किया गया, धमकियां दी गईं और रिश्वत देने की कोशिश की गई."

लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि न्यायाधीश पर हमला करने में विधानसभा में सभी पक्ष एकमत हो गए थे. इस सिलसिले में तमाम विशेषाधिकार प्रस्ताव रखने वाले शेतकरी कामगार पक्ष के नेता केशवराव धोंडगे ने तो यहां तक कहा कि बंबई की वेश्याएं भी लेंटिन के समर्थन में जुटे इन वकीलों से अधिक नैतिक हैं. बंबई की बार एसोसिएशन ने इस टिप्पणी का कड़ा विरोध किया है.

वैसे इस बार उन नेताओं, अधिकारियों और नकली दवा निर्माताओं का भविष्य दांव पर लगा है जिन्हें लेंटिन आयोग ने

विधानसभा के सभी सदस्यों ने पार्टी भेदों को भुलाकर एकमत से न्यायिक आयोग की रिपोर्ट का विरोध किया

दोषी पाया है. नेताओं की इस सूची में सबसे अव्वल हैं— पूर्व स्वास्थ्यमंत्री भाई सावंत, जिन पर लेंटिन ने भ्रष्टाचार के आरोप सही पाए. नतीजतन रिपोर्ट आते ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा.

शेतकरी कामगार पक्ष के नेता धोंडगे ने पिछले साल जुलाई में भी उस समय विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया था जब सावंत ने विधानसभा में आरोप लगाया था कि भाजपा नेता राम कापसे लेंटिन आयोग को झूठी जानकारियां दे रहे हैं. लेंटिन ने इस आरोप का खंडन किया. धोंडगे ने तुरंत इस आधार पर विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने विधानसभा अध्यक्ष से प्रमाणित बयान आने से पहले ही विधानसभा की कार्रवाई पर टिप्पणी कर दी है. लेकिन इस नोटिस पर बहस नहीं हुई. अप्रैल में धोंडगे ने फिर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव रखा और 50 मिनट के अपने भाषण में लेंटिन पर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तीखे प्रहार किए. गिने-चुने सदस्य ही लेंटिन के पक्ष में बोले. भाजपा विधायक राम कापसे ने रसीद बहियों का बंडल पेश करके दावा किया कि यह स्वास्थ्यमंत्री राम मेघे के भी उन भ्रष्ट ट्रस्टों से जुड़े होने की बात उजागर करता है. लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने घोषणा की कि वे इस विशेषाधिकार प्रस्तावों पर अपना फैसला अगले सत्र तक सुरक्षित रख रहे हैं.

सत्र खत्म होने के अगले दिन ही टाटा मेमोरियल अस्पताल में एक और हादसे की खबर ने शायद यह बता दिया कि लेंटिन आयोग की सिफारिशों को यथाशीघ्र लागू करने की जरूरत है. रक्ताल्पता के इलाज के लिए बच्चों को एक दवा का इंजेक्शन देने के बाद दो बच्चे मर गए और सात की हालत गंभीर हो गई. मुख्यमंत्री चव्हाण ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए वचनबद्ध है.

लेंटिन ने अपनी 289 पेज की रिपोर्ट भी चव्हाण द्वारा आयोग को दिए गए सहयोग के लिए आभार प्रकट करने के साथ ही शुरू की है. कुल मिलाकर मुख्यमंत्री की वजह से कम-से-कम न्यायाधीश का उद्यम निरर्थक तो नहीं जाएगा.

—एम. रहमान

केरल

'भक्त' मार्क्सवादी

सरकारी हस्तक्षेप का विरोध

केरल के मार्क्सवादी मंदिरों में जाने लगे हैं. पर आस्थावान इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं. वजह, मार्क्सवादी मंदिरों के प्रशासन पर कब्जा कर रहे हैं.

सत्तारूढ़ वामपंथी लोकतांत्रिक मोर्चे ने 23 मार्च को गुरुवायूर श्रीकृष्ण मंदिर की प्रबंध समिति को पुनर्गठित करके खुद को बखेड़े में फंसा लिया. इस कार्रवाई से राज्य के हिंदू संगठन भड़क उठे हैं. वे आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने कानून का उल्लंघन किया है. प्रबंध समिति के कानून के मुताबिक सिर्फ ऐसे ही लोग मंदिर की समिति में शामिल हो सकते हैं जो भगवान और मंदिर के रिवाजों में आस्था रखते हों. नई समिति के अध्यक्ष ने पहले ही घोषणा की है कि वे 'भगवान में आस्था रखने वाले मार्क्सवादी' हैं.

माकपा राज्य के इस सबसे धनी मंदिर को किसी भी तरह अपने कब्जे में लेना चाहती थी. इससे पहले तक यह पूर्व इंका मुख्यमंत्री के. करुणाकरन की जैसे जागीर ही थी और राजनीति के लिहाज से इसे उनसे छीनना बहुत मायने रखता था. दूसरी बात यह है कि मंदिर की सालाना आमदनी आठ करोड़ रुपए है.

इसलिए जैसे ही इसकी प्रबंध समिति का कार्यकाल खत्म हुआ, मार्क्सवादी इसमें घुस गए. उस समय तक इसके अध्यक्ष थे—करुणाकरन के नजदीकी इंका विधायक मोहन कृष्णन. सरकार को मंदिर पर कब्जा जमाने में कायदे से कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि गुरुवायूर मंदिर की नौ सदस्यीय प्रबंध समिति में पांच सदस्य वही मनोनीत करती है.

लेकिन भगवान कृष्ण के एक भक्त और करुणाकरन के नजदीकी कहे जाने वाले के.एम. वासुदेवन भट्टतिरीपाद ने केरल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर दी कि राज्य के देवस्वम मंत्री विश्वनाथ मेनन ईश्वर में आस्था नहीं रखते इसलिए उन्हें मंदिर की प्रबंध समिति में सदस्य मनोनीत करने का कोई अधिकार नहीं. इस पर हाईकोर्ट ने शिक्षामंत्री, जनता पार्टी के नेता के. चंद्रशेखरन से, जो 19 सदस्यीय मंत्रिमंडल के 15 हिंदुओं में अकेले 'आस्थावान' मंत्री हैं, सदस्य मनोनीत करने के लिए कहा. लेकिन चंद्रशेखरन ने मेनन की सारी सिफारिशों को ही मंजूरी प्रदान कर दी.

हालांकि सदस्यों की नामजदगी को लेकर मोर्चे में ही कलह भी हो गई. माकपा चाहती थी कि उसका आदमी ही समिति का अध्यक्ष बने, जबकि भाकपा के मलयट्टूर रामकृष्णन खुद अध्यक्ष बनना चाहते थे. पर माकपा के सामने भाकपा को झुकना पड़ा और रामकृष्णन का नाम वापस ले लिया गया. आखिर माकपा के अध्यापक संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर पी.एन. नारायणन को मंदिर की प्रबंध समिति का अध्यक्ष चुना गया.

अपनी ही पार्टी— भाकपा— के रवैये से खफा रामकृष्णन ने न सिर्फ पर्यटन विकास निगम की अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया बल्कि पार्टी भी छोड़ दी. इधर सत्तारूढ़ मोर्चे के आलोचकों ने आरोप लगाया कि नारायणन का चुनाव गैरकानूनी है क्योंकि रामकृष्णन के नाम वापस ले लेने की वजह से चुनाव के समय समिति पूरी तरह गठित नहीं थी. मामला अब अदालत में है.

पर राज्य के हिंदू इस बात से बेहद नाराज हैं कि मार्क्सवादियों ने अनुसूचित जाति के सदस्य के तौर पर थोप्पिल थंपी को नामजद किया जो जन्म से ईसाई हैं.

गुरुवायूर मंदिर में श्रद्धालु और (इनसेट) नारायणन

इसी बीच आलोचकों ने आरोप लगाया है कि सरकार ने मंदिर के अधिकारियों से रोजाना का चढ़ावा राष्ट्रीयकृत बैंक के बजाय सरकारी खजाने में जमा कराने को कहा है. बचाव में नारायणन कहते हैं, "मंदिर के पैसे को सरकारी खजाने में जमा कराना गलत नहीं. वह भी राष्ट्रीयकृत बैंक की तरह ही है." मार्क्सवादियों की दलील है कि वे सिर्फ मंदिर की आमदनी का प्रबंध ही देखना चाहते हैं. रोजमर्रा के धार्मिक अनुष्ठान से उनका कुछ लेना-देना नहीं. पर मंदिर को सरकारी शिकंजे से निकाल पाना कठिन है. मार्क्सवादी नेताओं का कहना है कि जितने हिंदू देवता हैं उतने ही हिंदू संगठन भी. ऐसे में यह तय कर पाना काफी मुश्किल है कि मंदिरों का जिम्मा किस संगठन को सौंपा जाए.

राज्य के हिंदू संगठनों का मोर्चा बनने की संभावना नहीं है इसलिए फिलहाल 'भगवान में आस्थावान' मार्क्सवादियों और श्रद्धालुओं के सामने मिल-जुलकर रहने के अलावा कोई चारा नहीं है.

—श्रीधर पिल्लै, गुरुवायूर में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मध्य प्रदेश

निशाने पर अर्जुन

वोरा-सिंधिया अभियान जोरों पर

एक महीने से भी ज्यादा अरसे से रेल राज्यमंत्री माधवराव सिंधिया और स्वास्थ्य व परिवार कल्याणमंत्री मोतीलाल वोरा मध्य प्रदेश के दौरे पर दौरे किए जा रहे हैं. वे "कांग्रेस (इ) की छवि चमकाने, उसके लिए समर्थन जुटाने और राज्य प्रशासन को पुख्ता बनाने के लिए" अपने समर्थकों को इकट्ठा कर रहे हैं. लेकिन हकीकत में इन दौरों की आड़ में उन्होंने अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी, मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह पर हल्ला बोल रखा है, राज्य से ही चुने गए अपने इन समर्थकों को इकट्ठा कर रहे हैं. दोनों केंद्रीय मंत्रियों का मानना है कि मुख्यमंत्री ने जानबूझकर वोरा समर्थकों को मंत्रिमंडल में नहीं लिया और उन्होंने मध्य भारत में भी सिंधिया के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है. राज्य के वे

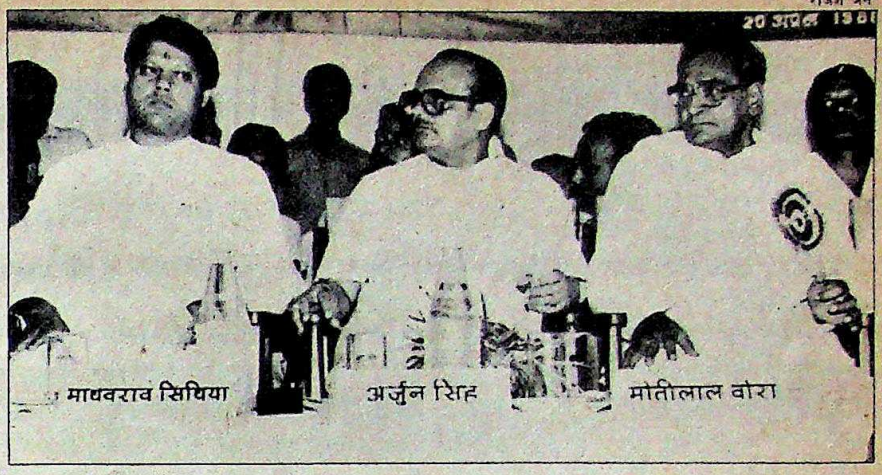

भोपाल रैली में सिंधिया, सिंह और वोरा

80 असंतुष्ट इंकाई भी उनके साथ हो लिए हैं जिन्हें तीन साल पहले विधानसभा चुनावों में अर्जुन सिंह ने टिकट नहीं दिए थे.

करीब 20 सांसदों और 60 विधायकों का समर्थन पाने के इस अभियान से बौखलाकर मुख्यमंत्री 11 अप्रैल को नई दिल्ली पहुंचे. उन्होंने प्रधानमंत्री राजीव गांधी को राज्य के हालात की जानकारी दी और अपने खिलाफ चल रहे अभियान से हो रहे नुकसान का ब्यौरा भी दिया. पर इस मुलाकात का नतीजा कुछ निकला नहीं दिखता क्योंकि अर्जुन सिंह के खेमे पर चांदमारी अभी जारी है.

नागरिक उड्डयन मंत्रालय के विमान और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हुए दोनों मंत्री मई आते-आते पूरे राज्य का दौरा कर डालेंगे. दो महीने पहले ही केंद्रीय सरकार में पहुंचे वोरा ने तबसे राज्य के नौ चक्कर लगा लिए हैं. सिंधिया समर्थकों का दावा है कि उन्हें गृहमंत्री बूटा सिंह, इस्पात व खनन राज्यमंत्री माखनलाल फोतेदार, सूचना व प्रसारणमंत्री हरकिशन लाल भगत

रायगढ़

अनोखा दलबदल

मध्य प्रदेश में रायगढ़ जिले के भाजपा अध्यक्ष 42 वर्षीय शत्रुजीत नायक दल बदलकर इंका में शामिल हो गए. 10 अप्रैल को रायगढ़ के निकट आयोजित एक सार्वजनिक सभा में उन्होंने यह घोषणा की. और तो और, मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह विशेष विमान से उड़कर इस मौके पर उन्हें हार पहनाने वहां पहुंचे.

मगर सारी खुशी जल्दी ही काफूर हो गई. अगले रोज नायक ने फिर पाला बदल लिया. उन्होंने आरोप लगाया कि बंदूकधारी इंकाइयों ने उनका अपहरण कर लिया था और उन्हें प्रलोभन दिए.

नायक के इस तेवर ने मुख्यमंत्री के लिए नया सिरदर्द पैदा किया. वे रायगढ़ जिले के खरसिया हलके से विधानसभा उपचुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर चुके हैं. मगर भाजपा जिला अध्यक्ष नायक का भी इस इलाके में काफी दबदबा माना जाता है. दलबदल कराने की वजह भी शायद चुनाव में अर्जुन सिंह के हाथ मजबूत करना था. पर चाल उलटी पड़ी और मुख्यमंत्री अपने ही दांव में फंस गए. वे कहते हैं, "आइंदा मैं कभी किसी भाजपाई पर विश्वास नहीं करूंगा."

मुख्यमंत्री ने इस बात का खंडन किया कि भाजपा नेता पर दलबदल के लिए दबाव डाला गया था. उनका कहना है, "नायक 27 मार्च को मुझसे भोपाल में मिले और बाद में उन्होंने पार्टी में शामिल होने की इच्छा प्रकट करते हुए एक चिट्ठी भी लिखी." पूरे मामले को एक अनोखा मोड़ देते हुए उन्होंने दावा किया कि दरअसल भाजपा ने ही नायक का अपहरण करके उन्हें अपना इरादा बदलने पर मजबूर किया है. मुख्यमंत्री ने मामले की न्यायिक जांच के आदेश भी दिए हैं. दलबदल की जांच करने वाला शायद यह पहला न्यायिक आयोग होगा. इसे तीन महीने में अपनी रिपोर्ट देनी है.

नायक ने इस बात की पुष्टि की है कि घटना से एक हफ्ता पहले वे इंका नेताओं के साथ कई बैठकें कर चुके थे. उन्होंने दलबदल के प्रस्ताव के बारे में भाजपा नेताओं को सूचित नहीं किया, क्योंकि यह बात इंका के हलकों में भी गोपनीय रखी गई थी.

मजे की बात यह है कि भाजपा इस सिलसिले में नायक को नहीं बल्कि अर्जुन सिंह को दोषी ठहरा रही है. बहरहाल, नायक के दावे अगर संदेहास्पद हैं तो मुख्यमंत्री की भी इस प्रकरण से कोई अच्छी छवि नहीं बनती. —नरेंद्र कुमार सिंह

रायगढ़ के जिला भाजपा अध्यक्ष नायक का दलबदल कराना मुख्यमंत्री को महंगा पड़ा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

और इंका कोषाध्यक्ष सीताराम केसरी जैसे अर्जुन सिंह विरोधियों का समर्थन हासिल है.

हैरत की बात तो यह है कि आलाकमान भी सिंधिया को वैकल्पिक मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने वाले असंतुष्टों की बात पर ही सहानुभूति से ध्यान दे रहा है. जब से अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री बने हैं उनके विरोधियों के लिए पार्टी अध्यक्ष राजीव गांधी से मुलाकात करना आसान हो गया है. एक जाने-माने असंतुष्ट नेता के.पी. सिंह कहते हैं, "हमारी सुनवाई होने लगी है और फिर अर्जुन सिंह के खिलाफ मिलने वाली शिकायतों पर इंका महासमिति भी कान धरने लगी है." मगर मुख्यमंत्री बेपरवाह होने का स्वांग भर रहे हैं. वे कहते भी हैं, "मुझे इसकी रत्ती भर चिंता नहीं है."

तिस पर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन दौरों से पार्टी के भीतर चल रही उठापटक बढ़ी है. दोनों गुटों के मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं. और पिछले पखवाड़े तो मुख्यमंत्री की परेशानियां और बढ़ गईं. दोनों मंत्री जब भोपाल पहुंचे तो हवाई अड्डे पर उनके स्वागत के लिए हजारों कार्यकर्ता जमा थे. दोनों मंत्रियों को जुलूस में राजभवन ले जाया गया. इस जोरदार स्वागत से वोरा और सिंधिया भी हैरत में पड़ गए.

मजे की बात यह है कि दोनों मंत्री दावा कर रहे हैं कि उनके दौरों का मकसद राज्य सरकार को अस्थिर बनाना नहीं है. सिंधिया बड़ी सज्जनता से कहते हैं, "हम पार्टी की नीतियों का प्रचार ही तो कर रहे हैं. इससे सरकार कैसे कमजोर हो सकती है?" अपने भाषणों में दोनों अपने विरोधी का नाम लेने से बचते हैं. आलोचना भी वे हमेशा बड़ी होशियारी से करते हैं. मसलन सिंधिया जनसभाओं में मौजूदा सरकार के बारे में तो चुप्पी साधे रहते हैं पर पूर्व मुख्यमंत्री की बढ़-चढ़कर तारीफें करते हैं. वे कहते हैं, "वोरा तो आम आदमी के मुख्यमंत्री थे. वे ईमानदार और आदर्श मुख्यमंत्री ही थे."

पर उनके कुछ साथी जरा ज्यादा ही बड़बोले हैं. छत्तीसगढ़ भाजपा के एक नेता के दलबदल की मुख्यमंत्री की कोशिशों पर एक सांसद प्रताप भानु शर्मा कहते हैं, "दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि एक तरफ प्रधानमंत्री ने ऐसे आचरण के खिलाफ कानून पास करवाया है और दूसरी तरफ अर्जुन सिंह इस तरह की राजनीति खेल रहे हैं."

मोर्चाबंदी हो चुकी है. अब बारी मुख्यमंत्री की है और वे हैरतअंगेज चाल चलने के लिए मशहूर हैं भी.

—नरेंद्र कुमार सिंह

गुजरात

'होनहार' छात्र

मुख्यमंत्री के साहबजादे जो हैं

गुजरात की शिक्षा व्यवस्था को घुन लग गया है. पिछले पखवाड़े यह हकीकत राज्य के एक मेडिकल छात्र की 'सफलता' से उजागर हो गई. छात्र भी कोई और नहीं बल्कि मुख्यमंत्री अमर सिंह भीलाभाई चौधरी का एमबीबीएस के तृतीय वर्ष में पढ़ रहा 'होनहार' बेटा तुषार है. पिछले साल दिसंबर में उसने फार्माकोलॉजी का पर्चा आखिर पास तो कर लिया पर इस सिलसिले में कई संस्थानों की दुर्दशा के बारे में कई अप्रिय सवाल खड़े कर दिए.

चौधरी (ऊपर) और शाह

गुजरात हाईकोर्ट में दायर दो याचिकाओं ने मुख्यमंत्री के बेटे के परीक्षा परिणामों पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है. विश्वविद्यालय अधिकारी भी कठघरे में हैं

उसे पास कराने के लिए विश्वविद्यालय के नियमों का किस कदर उल्लंघन किया गया, इसका भंडाफोड़ करने का श्रेय 'इंडियन एक्सप्रेस समूह' के गुजराती दैनिक 'जनसत्ता' को है. 18 अप्रैल को यह सनसनीखेज खबर छपने के बाद तो तूफान ही खड़ा हो गया और विश्वविद्यालय अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए दो याचिकाएं गुजरात हाईकोर्ट में दायर की गईं.

1983-84 में उसे अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित कोटे के तहत वडोदरा मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला. जून 1987 में दूसरे साल की परीक्षा में वह फार्माकोलॉजी में फेल हो गया.

पिछले साल दिसंबर में तुषार विशेष तैयारी के साथ फिर परीक्षा में बैठा पर इस बार उसे पहले से भी तीन अंक कम मिले. उसकी खुशकिस्मती से ऐन इसी समय महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर एस.के. शाह ने तदर्थ समिति की बैठक बुला ली. समिति ने फार्माकोलॉजी में फेल हुए छात्रों को अनुग्रह अंक के रूप में 10 अतिरिक्त अंक देने का फैसला कर डाला.

इसके बावजूद तुषार को पांच अंक कम पड़ रहे थे. लेकिन उसे अनुग्रह अंक देकर पास कर दिया गया. इसके अलावा दूसरे आरोप भी लगाए जा रहे हैं. पिछले साल अधिकारियों ने महज दो साल के अनुभव वाले एक सहायक प्रोफेसर को विधि चिकित्सा विषय का परीक्षक नियुक्त किया था. तुषार इसी विषय का पेपर दे रहा था.

'जनसत्ता' में खबर छपते ही चौधरी भागे-भागे वडोदरा पहुंचे. तीन दिन बाद विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार आर. कोठारी ने एक बयान जारी किया कि अनुग्रह अंक देना कोई असामान्य बात नहीं, ऐसे अंक पहले भी दिये जा चुके हैं.

आरोपों को इस तथ्य से भी बल मिला है कि राज्य सरकार करीब छह महीने से कुलपति पद के उम्मीदवारों को ललचाते आ रही है. और शाह उन तीन उम्मीदवारों में से हैं जिनके नाम चयन समिति ने इस पद के लिए सुझाए थे. विरोधियों का आरोप है कि शाह ने अपनी महत्वाकांक्षा के चलते इस घोटाले पर परदा डालने की कोशिश की है. शाह ने इन आरोपों का जोरदार खंडन किया. लेकिन अमरसिंह चौधरी ने इस पर किसी तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त करने से एकदम इनकार कर दिया.

लेकिन हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं ने मुख्यमंत्री को कठघरे में ला खड़ा किया है. एक याचिका में तुषार और विश्वविद्यालय के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग है तो दूसरी में तुषार की उत्तर-पुस्तिकाओं और संबंधित दस्तावेजों को अदालत में पेश करने की. यह चौधरी परिवार के लिए तीखा सबक साबित हुआ है.

—उदय माहूरकर, वडोदरा में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नई रणनीति, नई कामयाबियां

पंजाब की घटनाओं को लेकर लोग-बाग इन दिनों बेहद चिंतित हैं. रोज कुछ न कुछ वहां हो जाता है. सुबह के अखबार पढ़कर वे सोचने लगते हैं, "सरकार ने राज्य के प्रति ठीक नीति अख्तियार भी की है या नहीं?"

यह जानने के लिए हमने भांति-भांति के जानकार भाइयों का इंटरव्यू लिया. हमें यह बताते हुए खुशी हो रही कि सब कुछ ठीकठाक है. कई अति-विशिष्ट लोगों ने जो कुछ हमें बताया उसका सार यों है:

सबसे पहले हमने प्रधानमंत्री से बातचीत की. राजीव गांधी ने हमें बताया, "बेहद महत्वपूर्ण काम तो लोगों को सचेत करना है, उन्हें यह बताना है कि कैसे पाकिस्तान आतंकवादियों की सहायता कर रहा है. मुझे खुशी है कि हमने इस दिशा में काफी प्रगति की है. इस मामले में हमने भारी तादाद में लोगों को कायल किया है."

"सर! लोगों से आपका अभिप्राय सिखों और हिंदुओं दोनों से है क्या?"

"नहीं-नहीं," प्रधानमंत्री ने तुरंत सफाई दी, "मेरा मतलब है जापानी और वियतनामी दोनों..."

इसके बाद हमने पंजाब के तत्कालीन पुलिस महानिदेशक जूलियो फ्रांसिस रिबेरो से मुलाकात की. "चिंता की कोई बात नहीं," उन्होंने हमें आश्वासन दिया, "हमने गोली के बदले गोली वाला रवैया छोड़ दिया है. हमने समझ लिया कि इससे काम नहीं चलने वाला और कामयाबी नहीं मिलने वाली. इसलिए आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए अब हमने एक नई रणनीति अख्तियार की है."

"पर, साहब! इस बारे में आप विस्तार से कुछ कहेंगे?" हमने पूछा.

"क्यों नहीं, हमारा काम ही बताना है! अब हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि रॉकेट के बदले रॉकेट वाला रवैया ही कारगर रहेगा."

उधर जब हम राज्यपाल सिद्धार्थशंकर राय से मिले तो वे नितांत दार्शनिक मूड में थे. चिंतामग्न होकर वे बोले, "कोई भी मेरी इस बात से सहमत होगा कि किसी को अनिश्चित काल तक बंदी बनाकर नहीं रखा जा सकता. आखिरकार अनुचित तौर पर बंदी बनाए गए व्यक्ति को बंधनमुक्त करना ही होगा, भले ही इस समय उसे बांधे रखना बेहद जरूरी दिख पड़ता हो!"

"सर! आपका मतलब है कि एक दिन उन्हें सिमरनजीत सिंह मान को भी बंधनमुक्त करना पड़ेगा?"

"नहीं-नहीं," राय अपनी आंसू भरी आंखों से तकते हुए बोले, "मेरे कहने का अभिप्राय है कि एक दिन उन्हें मुझे भी बंधनमुक्त करना पड़ेगा. तब मैं यह बंदीगृह छोड़कर कलकत्ता में अपने घर जा सकूंगा और फिर से सुख-चैन की जिंदगी बसर कर सकूंगा."

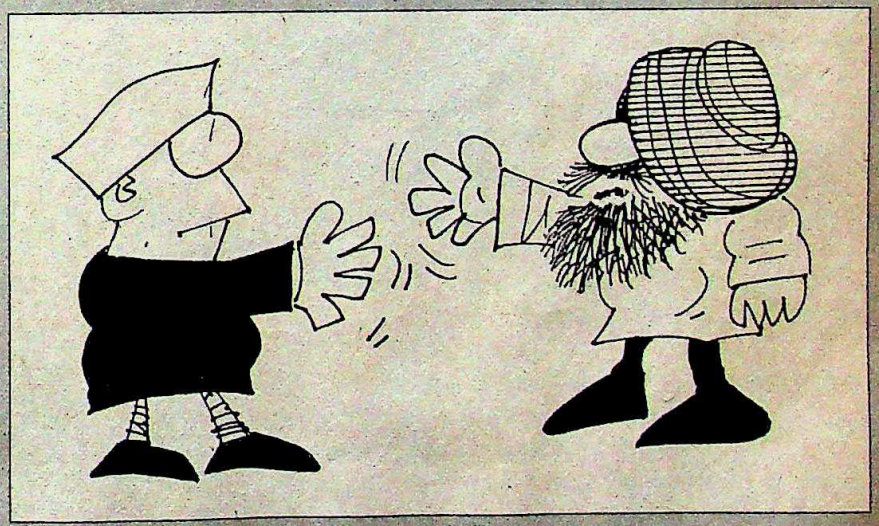

पर गृहमंत्री बूटा सिंह के यहां जब हम पहुंचे तो उन्होंने अलग ही राग अलापना शुरू किया. कहने लगे, "बड़ी समस्या तो आतंकवादियों और कुछ अकाली नेताओं के बीच करीबी ताल्लुकात की है. मेरा ख्याल है कि हम ये ताल्लुकात तोड़ने में कामयाब रहे हैं."

"तो अब कोई ऐसा आतंकवादी नहीं बचा जिसके संपर्क नेताओं से हों?" हमने सवाल किया.

"नहीं, एक भी नहीं, सिवा कुलदीप कौर के," और उसके संपर्क मेरे साथ हैं."

हमने गृह राज्यमंत्री चिदंबरम का इंटरव्यू भी लिया. उनकी बांछें खिली हुई थीं. तरंग में वे बोले, "जब से मैं इस मंत्रालय में आया हूं, स्थिति में नाटकीय सुधार हुआ है. जिस समय मुझे यह विभाग सौंपा गया था तब कहा जाता था कि पंजाब देश का सबसे विस्फोटक राज्य है. अब देखिए उन लोगों ने अपनी राय कैसे बदल ली है!"

"किस तरह, सर!"

"अब वे कहते हैं कि तमिलनाडु देश का सबसे विस्फोटक राज्य है..."

मुलाकात के दौरान ज्ञानी जैल सिंह ने ईर्ष्या से सरकार की तारीफ की, "मानना ही पड़ेगा कि सरकार की कोशिशों का नतीजा बेहद लाभदायक रहा है. मैं भी होता तो इससे बेहतर नहीं कर पाता!"

"तो, सर! आपके कहने का मतलब है कि सरकार की नीतियों के कई नतीजे निकले हैं?"

"नहीं! मेरा ख्याल है कि सरकारी नीतियों ने अनेक बयानबाजियों को जन्म दिया है..."

और अंत में हमने पंजाब के एक आम नागरिक का इंटरव्यू लिया. उसका कहना था, "सरकार पंजाब के बारे में अपनी नीति नहीं बदल सकती. यह असंभव-सी मांग है!"

"क्यों, ऐसा भी क्या है?"

"इसलिए कि पंजाब के बारे में पहले सरकार की कोई नीति तो हो..."

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कार्टून से बिफरे युवा इंकाई

व्यंग्यचित्र में दिखाया गया चेहरा बिलकुल प्रधानमंत्री जैसा था. लेकिन इसमें नाक लंबी दिखाई गई थी, बोफोर्स तोप की नली जैसी. और जंभाई लेते मुंह में स्विस बैंक दिखाया गया था.

जीवन बीमा निगम (एलआईसी) रायपुर के कर्मचारी संघ के सूचनापट पर लगा यह व्यंग्यचित्र मध्य प्रदेश के इंका नेताओं को बहुत नागवार लगा. 8 अप्रैल को वे इस 'भयानक व्यंग्यचित्र' को हटाने के लिए जिले के प्रशासनिक अधिकारियों से मिले. पुलिस

विनय शर्मा

बीमा कर्मचारियों की रैली और (इनसेट में) कार्टून

ने कर्मचारी संघ के नेताओं को धर दबोचा और कार्टून को हटा लेने के लिए 'दबाव' डाला. लेकिन इन नेताओं ने 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' का हवाला दिया.

दो दिन बाद युवा इंकाइयों ने एलआईसी कार्यालय को तहस-नहस कर डाला और व्यंग्यचित्र को चिंदी-चिंदी कर दिया. कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की. इस पर कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर रैली की.

विवादास्पद वायदा

गुजरात के मुख्यमंत्री अमरसिंह चौधरी ने पिछले पखवाड़े मानो बर्र के छत्ते को ही छेड़ दिया. आंबेडकर जयंती के अवसर पर एक सभा में उन्होंने वायदा कर डाला कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों को दी जाने वाली सुविधाएं अब उन लोगों को भी मिलेंगी, जो ईसाई बन चुके हैं. भाजपा की राज्य इकाई ने इस 'उदारता' की आलोचना करने में जरा भी देर नहीं लगाई. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शंकर सिंह वघेला गुस्से से कहते हैं, "सत्तारूढ़ दल सस्ती लोकप्रियता बटोरने की कोशिश कर रहा है. यदि यह नीति लागू कर दी गई तो इससे धर्म-परिवर्तन को बढ़ावा ही मिलेगा और सच्चे हकदार लोग इनसे वंचित रह जाएंगे."

शंकर सिंह वघेला

चौधरी की इस घोषणा का उनके दल के लोगों ने भी स्वागत नहीं किया. हालांकि खुलेआम किसी ने इसका विरोध नहीं किया लेकिन एक वरिष्ठ इंका नेता बोले, "ऐसा बयान देना घातक ही है." इसी समय चौधरी को पिछड़े वर्ग के लोगों की नाराजगी भी झेलनी पड़ी. ये लोग चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद किए गए वायदों को पूरा न करने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे.

विश्वनाथ हुए मात

इस बार बाजी उनके हाथ नहीं लगी. जनमोर्चा नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह को बिहार के मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद ने मात दे दी. परड़िया में दो महीने पहले हुए सामूहिक बलात्कार के मामले पर लोगों के जमीर को जगाने के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह पिछले पखवाड़े पटना पहुंचे.

वहां उन्होंने विपक्षी पार्टियों के समर्थकों के साथ जयप्रकाश नारायण की मूर्ति के सामने संकल्प लिया कि महिलाओं की इज्जत-आबरू की रक्षा के लिए सतत संघर्ष करते रहेंगे. कई विपक्षी गुटों के साथ वे धरने पर बैठे और एक मौन जुलूस की अगुआई भी की.

लेकिन तमाम विपक्षी प्रयासों के बावजूद परड़िया कांड 'बड़ा मुद्दा' नहीं बन सका तो इसका श्रेय मुख्यमंत्री आजाद द्वारा सही समय पर की गई कार्रवाइयों को जाता है. मुख्यमंत्री ने गांव का दौरा किया और आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ आरोप पत्र दर्ज करवा दिया. एक विशेष अदालत का भी गठन कर दिया गया.

मात खाए विश्वनाथ प्रताप सिंह को इस सवाल का भी जवाब देना पड़ा कि जब वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब माया त्यागी वाले मामले में उन्होंने क्या कार्रवाई की थी.

कलकत्ता में फोन महिमा

पिछले पखवाड़े कलकत्ता की कंज्यूमर यूनिटी ऐंड ट्रस्ट सोसाइटी (सीयूटीएस) ने एक अनोखी प्रतियोगिता आयोजित की. इसने देश के सभी टेलीफोन उपभोक्ताओं से प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए प्रवेशपत्र आमंत्रित किए. इसमें वादा किया गया कि सबसे ज्यादा समय तक जिसका टेलीफोन 'डेड' रहा हो और जिसने विभाग में सर्वाधिक शिकायतें दर्ज कराई हों ऐसे उपभोक्ता को इनाम दिया जाएगा. क्षेत्रीय टेलीफोन लोक अदालत में कंप्यूटर की मदद से सर्वोत्तम प्रविष्टि को आंका जाएगा. प्रधानमंत्री के तकनीकी

प्रभात परियार

पित्रोदा: उपभोक्ताओं में जागरूकता

सलाहकार सैम पित्रोदा खुद इस स्पर्धा के पुरस्कार देंगे.

सीयूटीएस के सचिव प्रदीप मेहता कहते हैं, "हमारा उद्देश्य उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा करना और टेलीफोन सेवाओं में बिना कोई सुधार किए किराए में बढ़ोतरी किए जाने का विरोध करना है." यह पूरी कवायद एक कार्यकुशल दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करने की पित्रोदा की योजनाओं का ही हिस्सा है. इस अभियान के अगले चरण में सीयूटीएस दाम बांधो आंदोलन छेड़ने की योजना तैयार कर रहा है.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सवारी वही जो हमेशा सबसे आगे जाए
इंजिन ऑइल वही
जो दुनिया में सर्वोत्तम कहलाए.

गल्फ प्राइड 2-T इंजिन ऑइल. सभी टू-स्ट्रोक इंजिनों वाले स्कूटर, मोटर सायकल, मॉपेड के लिए पेट्रोल में तुरंत घुल-मिल जाने वाला 2-T ऑइल. हर सावधानी से तैयार किया गया.

गल्फ प्राइड 2-T आधुनिक तकनीक वाले फार्मूले से बनाया गया है, जिससे शहर के थमते-चलते ट्रैफिक में इंजिन को पूरी सुरक्षा मिले, रफ्तार आसानी से बढ़े, पिकअप में ज्यादा तेजी आए, इंजिन को ज्यादा पावर मिले और इंजिन की देखभाल का खर्च घटे.

गल्फ प्राइड 2-T ऑइल से सवारी की शान बढ़े, इंजिन की जान बढ़े. आखिर यह फर्स्ट क्लास इंजिनों के लिए तैयार फर्स्ट क्लास इंजिन ऑइल जो है.

पेट्रोसिल ऑइल कं.लि. गल्फ ऑइल इंटरनैशनल कं., यू.एस.ए. के सहयोगी.

एवरेस्ट हाउस, ३, दिनशा वाच्छा रोड, बम्बई ४०० ०२०. फोन : २२०८१८, २३२३०३. टेलेक्स : ०११-३५२०.
क्षेत्रीय कार्यालय : नई दिल्ली • अहमदाबाद • कलकत्ता • मदास, पेट्रोसिल के डिपो डिस्ट्रीब्यूटर और स्टॉकिस्ट पूरे भारत में हैं. गल्फ ल्युब्रिकेन्ट सभी प्रमुख ऑटो स्पेयर पार्ट डीलरों के यहां भी मिलते हैं.

इंजिन हो जानदार, सवारी हो शानदार.

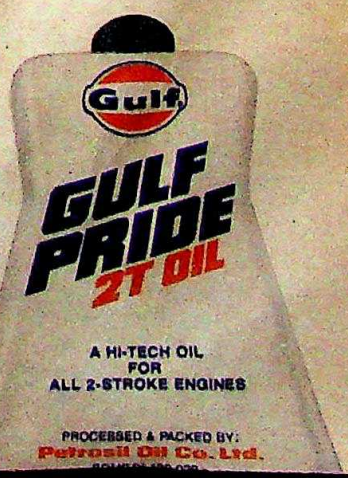

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

THE EDGE/B/88/POC/140 HN R

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

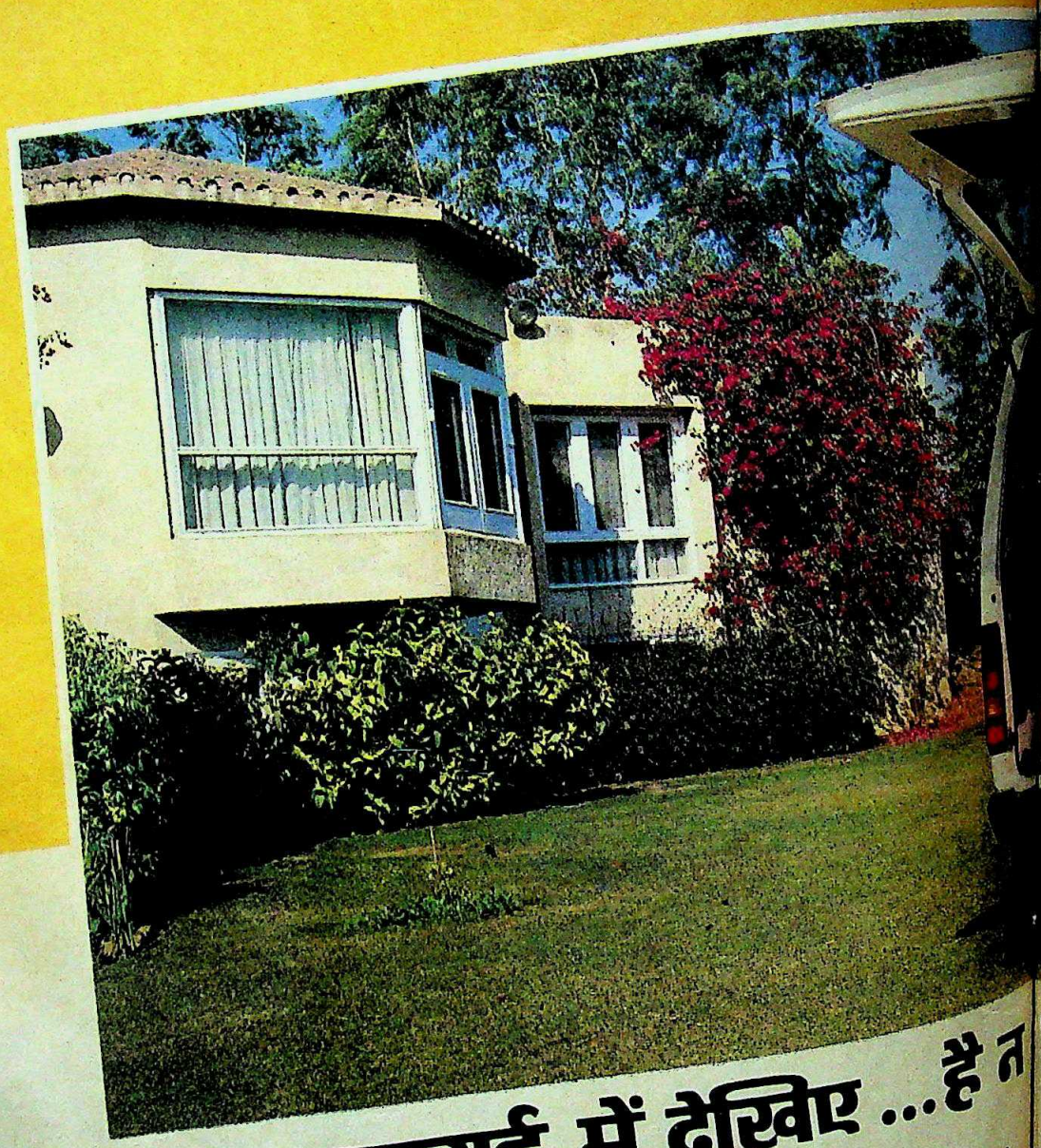

ज़रा गहराई में देखिए ...है न

आश्चर्य की बात है कि अधिकतर कारों में पाँचवां दरवाज़ा नहीं होता।
लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि इस कार में, चाहे इसे बूट लैच कहिए या डिक्की, यह एक सुविधाजनक प्रवेश-द्वार है—खासकर हंसते-खेलते, मौज मनाते बच्चों, और ढेर-सा-सामान-झट-खरीद-लेने-वाली श्रीमती जी के लिए।
जी हां, इसके खुलते ही कितनी खुली जगह मिल जाती है आपको! और जिस कार में इतनी खुली आरामदायक जगह के साथ मारुति की शानदार बनावट, उत्तम कार्यकुशलता, ईंधन का कुशलतम उपयोग और कार चलाने का असीम आनन्द हो तो मानना पड़ेगा कि यह एक सम्पूर्ण कार है। तभी तो इसे 'ओमनी' (अंग्रेजी भाषा का शब्द जिसका अर्थ है 'सर्वांगीण') का नाम दिया गया है।
इतने शानदार परिचय के बाद, आइए इसकी अन्दर की विशेषताओं पर गौर करें।

भीतरी-भाग: अनेक उपयोग

एक आम गणना के अनुसार ओमनी के भीतर का क्षेत्र 7.5 क्यूबिक मीटर होता है। पिछली सीट हटा दीजिए। लीजिए मारुति ओमनी सामान ले जाने वाली वैन, पिकनिक की गाड़ी या दूसरे शहर में जाने के लिए बड़ी कार के रूप में तैयार।
फिर भी आपके लिए यह फैमिली कार, ऑफ़िस कार, तथा शहर में दूर-सुदूर तक ले जाने वाली सुदृढ़ कार बनी रहती है।
वास्तव में, इसमें इतना अधिक स्थान होने की बदौलत आप इसका उपयोग जैसा चाहें कर सकते हैं।

मारुति ओमनी—चलाने में आराम

ओमनी चलाने का आनन्द ही कुछ और है। इंस्ट्रूमेन्ट पैनल सुन्दर और सुविधाजनक। स्टीयरिंग कॉलम की पोज़ीशन बिल्कुल सही। सीटों में फेर-बदल सम्भव। कन्ट्रोल लीवर, साथ-बियर शाफ्ट हाथ से छू लेने वाली दूरी पर।
और हाँ, सांस लेने के लिए भी बहुत खुला स्थान।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आज की सबसे खुली कार!

मारुति का अति कार्यशील सुज़ूकी इंजन

उच्चतम तौर पर 3 सिलेंडर, 4 स्ट्रोक, 800 सी सी का इंजन। अन्य शब्दों में यह है ईंधन की श्रेष्ठ कार्यकुशलता और उच्च क्षमता वाला इंजन। इसे बिना-परेशानी 1,50,000 किलोमीटर तक आराम से चलाया जा सकता है। इसके बाद इसे 'री-बोर' भी किया जा सकता है।

मारुति की विशेषताएं

सुरक्षा और मज़बूती मारुति की अनिवार्य विशेषताएं हैं, जबकि महत्त्वपूर्ण बात यह है कि ऐसी खूबियां अधिक मंहगी कारों में पाई जाती हैं।

* एक स्वतंत्र मैक्फ़र्सन स्ट्रट सस्पेंशन–अगली तरफ़, तथा लीफ़-स्प्रिंग टाइप सस्पेंशन-पिछली तरफ़।
* 30 सेंटीमीटर व्यास के 'ड्राप-सेंटर' पहिए सुरक्षापूर्ण ढंग से घूमने और कम जगह में आसानी से मोडने की सुविधा प्रदान करते हैं।
* 'सिंक्रोमेश' फॉरवर्ड गियर तथा दोहरा ब्रेकिंग सर्किट।
* ज़ंग से पूरी तरह बचाव के लिए इलेक्ट्रोफ़ोरेटिक पेन्ट से उपचारित फ्रेमवर्क।
* इंजन ठंडा रखने की विशेष व्यवस्था, जिससे रोज़-रोज़ रेडियेटर में पानी भरने की मुश्किल दूर हो जाती है।

मारुति ओमनी: निःसंदेह एक उत्तम कार। उससे भी उत्तम बात है इसका सबसे खुली कार होना।

(डी.जी.एस. एण्ड डी रेट कॉन्ट्रेक्ट पर भी उपलब्ध)

चित्र में दर्शाया गया सहायक सजावटी उपयोगी सामान ओमनी की बिक्री में शामिल नहीं।

MARUTI OMNI खुले आराम का सफ़र

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

मारुति उद्योग लिमिटेड, 11 वीं मंज़िल, जीवन प्रकाश, 25 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110 001

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

The Modern Man.

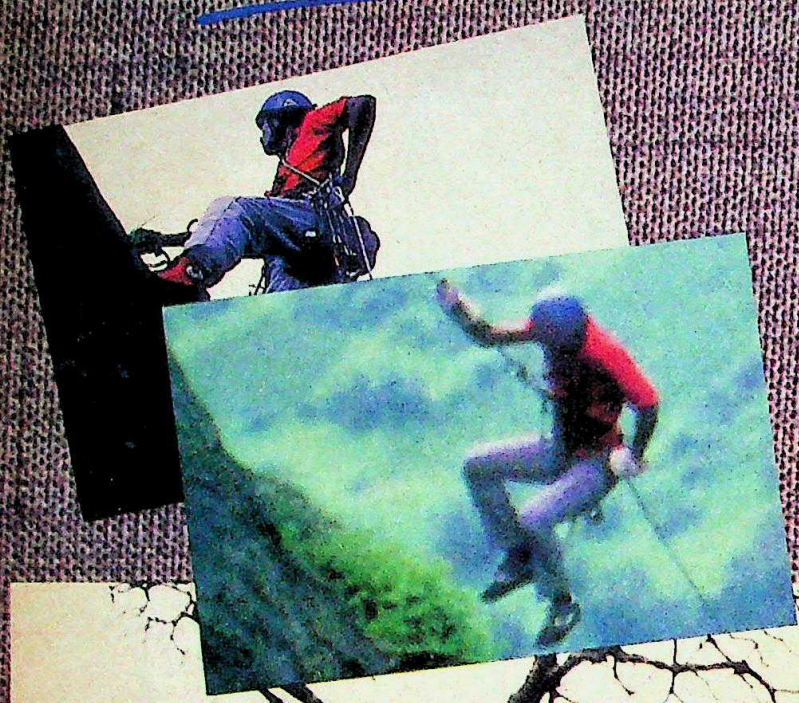

He has adventure in his heart and romance in his life.

Modern & Sulzer

SUITINGS · SHIRTINGS · SAFARIS

Modern Suitings Ltd, Alwar, Rajasthan.

Mukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आपसी कलह की कलई खुली

आंध्र प्रदेश में इंका के आखिरी मुख्यमंत्री के. विजयभास्कर रेड्डी द्वारा बगावत का झंडा फहरा देने के साथ ही पिछले पखवाड़े राज्य इंका की आपसी कलह खुलकर सामने आ गई. रेड्डी के हमले का निशाना बने केंद्रीय उद्योगमंत्री जे. वेंगलराव, जो प्रदेश इंका के अध्यक्ष भी हैं. उन पर इलजाम है कि वे 'निरंकुश अध्यक्षीय राज' चलाकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को न केवल दबा और सता रहे हैं बल्कि अपमानित भी कर रहे हैं.

बाबजी/जनता स्टुडियो

वेंगलराव (बाएं) और रेड्डीः आमने-सामने

15 अप्रैल को रेड्डी के घर पर पूर्व मंत्री, पूर्व इंका अध्यक्ष और इंका विधायक इकट्ठा हुए और उन्होंने पार्टी हितों की रक्षा न कर पाने के लिए वेंगलराव को जी भरकर कोसा. उनका कहना था कि वेंगलराव ने तेलुगु देशम पार्टी को कभी गंभीरता से नहीं लिया और न ही राज्य सरकार के चावल के थोक व्यापार को कृषक परिषद को सौंपे जाने के फैसले पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर की. उनका आरोप है कि उन्होंने राज्य में पार्टी के वोट बैंक हरिजनों पर हुए अत्याचारों पर भी गौर नहीं किया. इस मुहिम के तहत रेड्डी अब जल्दी ही असंतुष्टों को जमा करने की कोशिश करेंगे.

मराठवाड़ा में मिली मात

महाराष्ट्र में इंका की आशंकाएं अब हकीकत में बदलती जा रही हैं. 17 अप्रैल को हुए औरंगाबाद नगर निगम के चुनाव में शिवसेना ने 60 में से 27 सीटें जीत लीं. आपसी फूट के कारण मत्ताब्ढ़ इंका के हाथ 18 सीटें ही लगीं. भाजपा और जनता पार्टी का तो पत्ता साफ हो गया. इस तरह 25 प्रतिशत मुस्लिम आबादी और बड़ी संख्या में दलित तबके वाले इस शहर का प्रशासन शिवसेना अब चार निर्दलीय समर्थकों की मदद से चलाने की तैयारी कर रही है. शिवसेना के लिए इस जीत का महत्व ज्यादा ही है. यह उसकी बढ़ती लोकप्रियता का ही प्रमाण है.

ये चुनाव काफी तनावग्रस्त वातावरण में हुए थे. मतदान के दिन ही हिंसा भड़क उठी, जिसमें चार लोग मारे गए और लगभग तीस घायल हो गए. शिवसेना ने चुनाव प्रचार के दौरान 'गर्व से कहो हम हिंदू हैं' का कट्टरपंथी नारा देकर मतदाताओं का समर्थन जुटाया था. इंका को तो ये चुनाव महंगे ही पड़े. उसकी भीतरी कलह उजागर हो गई. उसके जिला अध्यक्ष समेत 42 बागी उम्मीदवार खड़े हो गए जिनमें से जिला इंका अध्यक्ष समेत पांच जीत भी गए.

ठाकरेः कट्टरपंथी नारा

आलोचना का बिल

प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने जब पिछले महीने घोषणा की कि वे गुवाहाटी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे तो असम गण परिषद (अगप) की सरकार उनके लिए एक मंच और पंडाल बनाने में जुट गई. इसके तुरंत बाद ही प्रधानमंत्री राज्य के 2,000 इंकाई कार्यकर्ताओं की सभा में बोलने वहां जा पहुंचे.

लेकिन वहां 8,000 लोगों की भीड़ देखकर राजीव गांधी क्षुब्ध हो गए और जुट गए अगप सरकार की आलोचना में. उन्होंने असम समझौता लागू करने में अगप सरकार को नाकाम ठहराया. आरोप लगाया कि उसने सत्ता हथियाने के लिए 'बहिरागतों' का प्रेत खड़ा किया. प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार को चुनौती दी कि वह अपने ही दावे को साबित करने के लिए राज्य में 20 लाख से 60 लाख बहिरागतों की शिनाख्त करके दिखाए. फिर उन्होंने इंकाइयों को आगामी लोकसभा चुनावों की तैयारी में जुटने का आह्वान किया.

राज्य सरकार को यह सब नागवार गुजरा, खासकर इसलिए कि प्रधानमंत्री ने यह दावा किया कि असम समझौते को लागू करने में केंद्र ने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी है. इससे क्षुब्ध होकर अगप सरकार ने प्रधानमंत्री की सभा के लिए पंडाल और मंच बनवाने में खर्च हुए 35,000 रुपए का बिल प्रदेश इंका को भेज दिया. मुख्यमंत्री प्रफुल्ल कुमार महंत ने कहा, "इंका को इसका भुगतान करना ही पड़ेगा, क्योंकि यह सभा मुख्यतः पार्टी की थी."

सूखती सुखना होगी लबालब

चंडीगढ़ की सुखना झील के सूखे तट पर पिछले पखवाड़े रंग-बिरंगे झंडे लहरा उठे. पंजाब के राज्यपाल सिद्धार्थशंकर राय ने नारियल फोड़कर 'सुखना बचाओ' अभियान की शुरुआत की. इस मौके पर श्रमदान करने वाले बड़ी संख्या में मौजूद थे. इसमें ज्यादातर सामाजिक कार्यकर्ता, छात्र और सरकारी कर्मचारी थे.

शहर के मुख्य प्रशासक अशोक प्रधान की प्रेरणा से शुरू हुआ यह अभियान 75 दिन तक चलेगा. पहले दिन से ही इसमें लोग

सुखना झील में कार्यरत स्वयंसेवकः सद्प्रयास

उत्साह से भाग लेने लगे हैं. स्कूटरों, साइकिलों और बसों में सवार हजारों लोग झील की ओर जाते देखे जा सकते हैं. लोगों के उत्साह को देखते हुए प्रशासन ने दुपहिया स्कूटर की पिछली सीट पर सवारी न बिठाने के आदेश में सुबह एक घंटे के लिए ढील दे दी है.

इस अभियान के तहत स्वयंसेवक नदी से गाद और मिट्टी खोदकर निकाल रहे हैं. इस कृत्रिम झील के दो द्वीपों से अब तक 40,000 क्यूबिक फुट गाद निकाली जा चुकी है. अंतिम लक्ष्य 90 लाख टन गाद निकालने का है.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जनरल के. सुंदरजी विवादों

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

की विरासत

स्वाभिमान, दूरदृष्टि, जोड़तोड़ की राजनीतिकों वाली निपुणता मगर एक तरह का अड़ियलपन भी—इन तमाम गुणों से संपन्न रोबीले व्यक्तित्व के धनी हैं 59 वर्षीय जनरल कृष्णास्वामी सुंदरजी. पिछले हफ्ते जब उन्होंने थलसेनाध्यक्ष के ओहदे से अवकाश ग्रहण किया तो वे अपने पीछे गंभीर विवादों की एक ऐसी विरासत छोड़ गए जिसकी मिसाल भारतीय सेना के किसी भी मुखिया के रिकार्ड से नहीं मिलती.

इसके कारण तलाशना कठिन नहीं है. सैम मानेकशॉ के बाद से अब तक के किसी भी थलसेनाध्यक्ष का व्यक्तित्व सुंदरजी जितना तड़क-भड़क वाला नहीं था. और तो और, सिर्फ अपने व्यक्तित्व के बूते राजनैतिक आकाओं को कायल करने में तो मानेकशॉ भी कामयाब नहीं हो पाए थे. और क्यों न हो, भारतीय सेना के किसी भी जनरल में शायद इतनी बौद्धिक गहराई और रणनीतिक समझ नहीं दिखी जितनी सुंदरजी में थी. इन्हीं विशेषताओं के कारण ही तो वे निर्विवाद रूप से 'विचारवान जनरल' माने जाते थे. अपने 820 दिनों के कार्यकाल में उन्होंने सेना की रणनीति, नजरिये और ढांचे में इतने अहम बदलाव ला दिए जितने अभी तक दूसरा कोई सेनाध्यक्ष नहीं ला पाया था.

और कोई सेनाध्यक्ष इतने विवादास्पद नहीं रहे जितने सुंदरजी. शायद किसी और सेनापति को इतनी रणनीतिक चुनौतियां नहीं झेलनी पड़ीं

लेकिन इन सारी बातों के साथ एक अहम तथ्य यह भी है कि किसी दूसरे सेनाध्यक्ष को शायद इतनी रणनीतिक चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा, इतनी दुस्साहसिक सीमाओं तक नहीं जाना पड़ा. 1962 की लड़ाई के बाद पहली बार सेना के जवानों के हौसले और हथियारों की इतनी कड़ी परीक्षा हुई. 1986 की सर्दियों में ऑपरेशन ब्रासटैक्स से जो सिलसिला शुरू हुआ तो उसके बाद सियाचिन की बियाबान पहाड़ियों में गुपचुप तीखी झड़पें चलती ही रहीं, भारत-चीन सीमा पर भारी तनाव बना रहा और श्रीलंका में ऑपरेशन पवन में तो 80,000 जवानों को दूसरे देश की जमीन पर जमे रहना पड़ा. और इन सबके ऊपर सैनिकों को अपने नायक द्वारा किए गए व्यापक परिवर्तनों के भी अनुरूप ढलना पड़ा.

इन्हीं परिवर्तनों पर आज सेना और रक्षा मंत्रालय के हलकों में भारी बहस छिड़ी हुई है. मतभेद, जाहिर हैं, बहुत स्पष्ट और तीखे हैं. सुंदरजी जैसे महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व के संदर्भ में यह स्वाभाविक भी है. वरिष्ठ जनरलों सहित सेना में ऐसे कई लोग हैं जो उन पर बेहद महत्वाकांक्षी होने और आत्मप्रदर्शन प्रेमी होने का आरोप लगाते हैं. उन पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि इतिहास पुरुष बनने की आकांक्षा में उन्होंने ऑपरेशन ब्रासटैक्स के दौरान देश को पाकिस्तान से युद्ध के कगार पर ही लाकर खड़ा कर दिया था.

लेकिन सेना में ऐसे लोग भी हैं जो मानते हैं कि उनकी अगुआई में सेना पहली बार 'वैचारिक प्रक्रिया' के दौर से गुजरी. वे पहले ऐसे सेनाध्यक्ष माने जाते हैं जिन्होंने 15 साल की दीर्घकालिक योजनाएं तैयार की, रणनीति और लामबंदी के नए और सनसनीखेज विचार दिए, रणनीति व हथियारों के मामले में आधुनिकीकरण को तेज किया और देश की भौगोलिक-राजनैतिक महत्वाकांक्षाओं में सेना की भूमिका को अहम बनाया.

अब इतिहास क्या कहेगा? क्या सुंदरजी एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे जिसने सेना को लगभग घसीटकर 21वीं शताब्दी के रास्ते पर चला दिया? या उन्हें एक ऐसे धुनी योद्धा के रूप में याद किया जाएगा जिसने न तो सलाहों की परवाह की और न परंपरा की और अपनी सहयोगी दूसरी दो सेनाओं तक का भी ख्याल नहीं रखा तथा जो व्यक्तिगत लक्ष्य के लिए सचाई को भी नकारता गया.

सुंदरजी के विचार और सेना पर उनका

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रभाव इतना दूरगामी और व्यापक है कि इतिहास ही उपरोक्त सवालों का माकूल जवाब दे पाएगा. वे खुद मानते हैं, "मैंने जानबूझकर अपने लक्ष्य बहुत ऊंचे रखे. यह सोचना भी यथार्थपरक नहीं होगा कि मैं उन सभी लक्ष्यों को पूरी तरह हासिल कर सकता था." इससे हुआ यह कि सुंदरजी की उपलब्धियां उनके वायदों की तुलना में कम ही रहीं. उन्होंने वरिष्ठ अफसरों और सेना के लंबे व गौरवशाली इतिहास के दौरान बने ढांचे में भी काफी उलटफेर कर दिया. उन्होंने वह सब किया जिसके कारण आरोप लगे कि उन्होंने एक साथ कई सुधार इतनी तेजी से लागू करने की कोशिश की जिन्हें भारतीय सेना जैसे विशाल संगठन के लिए पचाना तो दूर, समझ पाना भी जरा मुश्किल ही था. उच्च तकनीक, महंगे और भारी-भरकम अभियानों और सुधारों के लिए उनकी दीवानगी के कारण सेना की समग्र भूमिका की उपेक्षा ही हुई. सबसे बड़ी बात यह कि सुंदरजी ने बदलाव का जो सिलसिला शुरू किया वह आगे कभी अव्यावहारिक या अवास्तविक लगे तो उसमें किसी तरह का संशोधन लगभग असंभव ही होगा.

वैसे ये बदलाव अपने आप में महत्वपूर्ण और व्यापक असर वाले हैं. इनमें कुछ इस प्रकार हैं:—

► भविष्य में किसी भी आकस्मिक सैनिक अभियान की तैयारी और सेना को आधुनिक हथियारों से लैस करने की 15 वर्षीय दीर्घकालिक योजना. यह योजना नौसेना, वायुसेना, सुरक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और रक्षा उत्पादन संगठन पर भी समान रूप से लागू होती है.

► मशीनीकरण, लामबंदी की दिशा में अहम कदम और बख्तरबंद युद्ध की रणनीति को आधुनिक बनाने पर जोर.

► सेना के पहले मेकेनाइज्ड इन्फैंट्री डिवीजन का गठन.

► सेना के इतिहास में सबसे व्यापक और जटिल सैनिक अभ्यासों का आयोजन.

► सेना के नियंत्रण और निर्देशों पर चलने वाली 'सेना उड्डयन कोर' की स्थापना.

► कमांडरों के स्तर पर और मोर्चों पर भारी पैमाने पर कंप्यूटरीकरण ताकि मौके से बिलकुल ताजा सूचनाएं मिल सकें.

► थलसेना की 54 वीं डिवीजन का हवाई हमला डिवीजन के रूप में पुनर्गठन.

► थलसेना की एक विशेष व्यूहरचना 'रैपिड्स' (रिऑर्गनाइज्ड आर्मी प्लेन्स इन्फैंट्री डिवीजन) का विचार रखना. इस ठोस व्यूहरचना से सेना की मारक क्षमता, आधुनिकता, तेजी, लामबंदी, और धरती-आकाश युद्ध की क्षमता में वृद्धि होने की संभावना है.

► सेना की आगे बढ़ने की गति, बारूदी क्षमता और पैंतरेबाजी पर जोर देने वाली नई रणनीति का निर्धारण.

► कमांडरों के परंपरागत ढांचे का पुर्नगठन जिसके कारण अफसरों के मोर्चे और मुख्यालय के बीच तबादले शुरु हो गए.

► नई 'निवारक' नीति के तहत पाकिस्तान और चीन के लिए आक्रामक सैन्य मुद्रा.

► थलसेना के पैराशूट रेजीमेंट को ब्रिटिश स्पेशल एअर सर्विसेज की तरह तीन पैरा-कमांडो बटालियनों में बदलना.

ऑपरेशन ब्लूस्टार पर सुंदरजी की रणनीतिक सोच की स्पष्ट छाप थी, भारी हथियारों का बेहिसाब प्रयोग, खुफिया ब्यौरों की अनदेखी और अति आत्मविश्वास

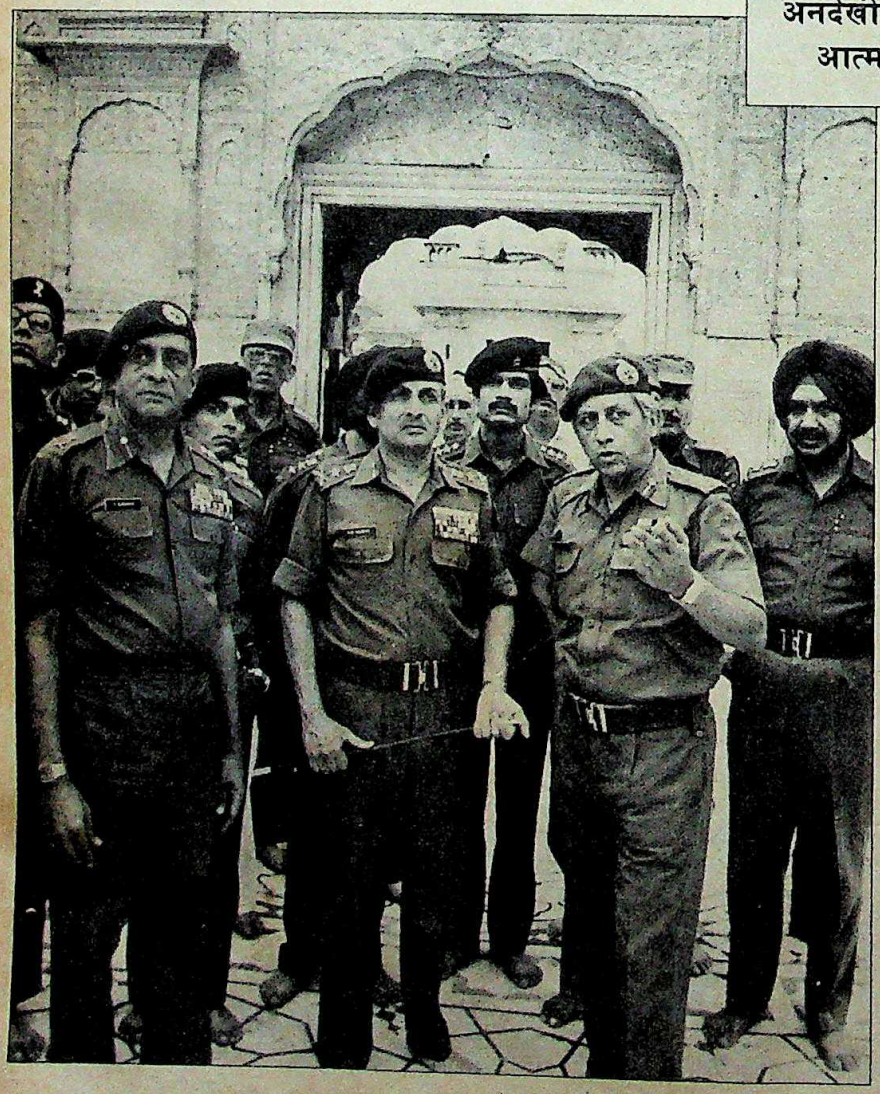

ऑपरेशन ब्लूस्टार के बाद स्वर्ण मंदिर में सुंदरजी (बाएं)

इसमें शक नहीं कि ये तमाम परिवर्तन अरसे से लटके पड़े थे और सैनिक माहौल के मद्देनजर जरूरी भी थे. रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान के निदेशक, एअर कमोडोर जसजीत सिंह कहते हैं, "मार्के की बात तो यह है कि तीन सेनाओं की सोच में अब अधिक एकरूपता आ गई है. इनमें अब अधिक एकजुटता और सामंजस्य की बातें होने लगी हैं." निस्संदेह इन सबका श्रेय सुंदरजी को जाता है. एक वरिष्ठ जनरल कहते हैं, "सुंदरजी की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि उन्होंने सेना में नए विचारों, नई रणनीति और भविष्य के बारे में सोच-विचार

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

का सिलसिला शुरू कराया.''

सेना के वरिष्ठ अफसर उन्हें श्रेय देने के मसले पर एकमत तो हैं लेकिन लगभग एक स्वर से वे उन्हें एक ऐसा अधिकारी भी कहते हैं जो अपनी सनक पर काम किया करता था और जिसकी महत्वाकांक्षाओं और ऊंचे विचारों के कारण सेना के लिए खतरा भी पैदा हो सकता था, बल्कि कुछ मामलों में तो यह होने भी लगा है. सुंदरजी के बारे में हमेशा से यही कहा जाता है कि जिस काम में हाथ डालने से पहले दूसरे लोग सौ बार सोचते उन्हें वे दूरगामी परिणामों की चिंता किए बगैर ही शुरू कर देते थे.

विवाद की जड़ भी यही है. 'इंडियन डिफेंस रिव्यू' के संपादक तथा सबसे प्रतिष्ठित सेना अफसरों में से एक, लेफ्टिनेंट जनरल मैथ्यू थॉमस कहते हैं, ''सुंदरजी हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं. उनमें हमेशा कोई भी काम ताबड़तोड़ करने और खबरों में बने रहने की धुन लगी रहती है.''

सुंदरजी के कार्यकाल की खासियत कुल मिलाकर यही रही है. पहली बार सुर्खियों में वे तब आए जब पश्चिमी कमान के प्रमुख के रूप में जून 1984 में उन्होंने स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लूस्टार की रणनीति तैयार की और उसका नेतृत्व किया. सामरिक और राजनैतिक दोनों पहलुओं से ब्लूस्टार का संचालन बहुत बुरा रहा. इस पर सुंदरजी के सामरिक सोच की पूरी छाप थी– भारी हथियारों का बेहिसाब प्रयोग, तार्किक और सुफिया ब्यौरों की बनदेखी और जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास. उन्होंने इंदिरा गांधी से यहां तक कह दिया था कि यह अभियान तो वे एक ही दिन में पूरा करके दिखा देंगे.

चतुराई भरा प्रस्तुतिकरण, शब्दाडंबर और आधुनिक सामरिक सोच की वजह से वे तब के रक्षा राज्यमंत्री अरुण सिंह के प्रिय पात्र बन गए थे

इस अभियान में शामिल रहे सेना के वरिष्ठ कमांडरों का कहना है कि इसे पर्याप्त सुफिया खबरों की जानकारी के बिना ही जल्दबाजी में शुरू कर दिया गया. कमांडो फोर्स को स्वर्ण मंदिर के सही नक्शे और रूपरेखा तक की जानकारी नहीं दी गई थी. जवानों को 1960 में बने पुराने गैसमारक और 1957 में बने धुंआ बम दिए गए जो फटे ही नहीं. दूसरी बड़ी गलती यह की गई कि उथले सरोवर में गोताखोर सैनिकों को घात लगाकर बैठने के लिए भेजा गया जहां वे चारों ओर छिपे हथियारबंद आतंकवादियों के लिए आसान निशाने ही थे. लेकिन सुंदरजी खुफियातंत्र के कमजोर होने की बात का एकदम खंडन करते हैं.

लेकिन इन सबके बावजूद सुंदरजी बड़े सम्मान के हकदार रहे. इसमें कोई शक नहीं कि वे ही एकमात्र जनरल थे जो स्वर्ण मंदिर में उचित समय या कार्रवाई के तौर-तरीके पर सोचे-समझे बिना ही घुस सकते थे. 'इंडिया टुडे' के साथ बातचीत में कई सैनिक अधिकारियों ने कहा है कि वह ऐसी स्थिति थी जहां सेना को अड़ जाना चाहिए था. एक जनरल कहते हैं, ''तब किसी में यह कहने का नैतिक साहस होना चाहिए था कि नहीं, यहां सेना का काम नहीं है, इसके राजनैतिक परिणाम देश के लिए भारी पड़ेंगे. कमांडर के स्तर पर आपको व्यापक राष्ट्रीय परिदृश्य को भी ध्यान में रखना पड़ता है.''

लेकिन सुंदरजी का सितारा पहले से ही बुलंदी पर था क्योंकि उन्होंने न सिर्फ राजनैतिक अलंबरदारों को प्रभावित कर

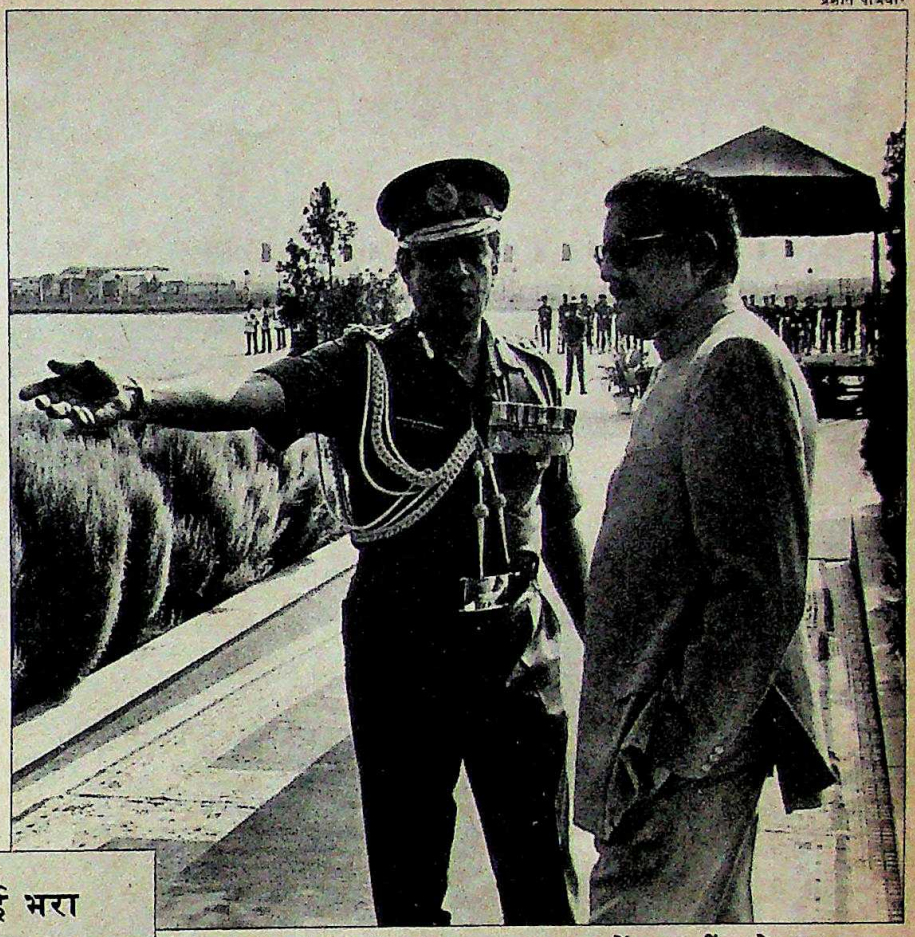

प्रभात पटियार

1986 में अरुण सिंह के साथ

रखा था बल्कि तत्कालीन थलसेनाध्यक्ष कृष्णाराव से भी उनकी अच्छी पटती थी. दोनों ही व्यक्ति महार रेजीमेंट से थे. पर सामरिक रणनीति बनाने में सुंदरजी की प्रतिभा तो जगजाहिर थी ही. उन्हें सेना के सबसे प्रतिष्ठित बख्तरबंद डिवीजन की कमान सौंपी गई और वे किसी बख्तरबंद डिवीजन की कमान संभालने वाले पैदल सेना के पहले अफसर थे. वे संयुक्त राष्ट्र संघ की सेनाओं के साथ कांगो में थोड़े समय के लिए रहे. महू इन्फैंट्री स्कूल, वेलिंगटन के स्टॉफ कॉलेज में प्रशिक्षक और कॉलेज ऑफ कांबेट में कमांडेंट रहे. उन्हें अमेरिका के फोर्ट लीवेनवर्थ की प्रतिष्ठित सैनिक संस्था अमेरिकन मिलिट्री इंस्टीट्यूट में एक कोर्स के लिए भी चुना गया था.

थलसेनाध्यक्ष कृष्णाराव के कार्यकाल में ही सुंदरजी ने साउथ ब्लॉक में अपनी अहमियत का एहसास कराना शुरू कर दिया था. उस समय उन्हें थलसेना का डिप्टी चीफ बनाया गया था. कई वरिष्ठ अफसरों के मुताबिक कृष्णाराव सुंदरजी पर बहुत हद तक निर्भर थे. उस समय सुंदरजी ही वास्तव में सेनाध्यक्ष का काम संभाल रहे थे. इस

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तरह सुंदरजी वरिष्ठ पदों की नियुक्ति पर फैसला लेने की स्थिति में आ गए थे. उनके विरोधियों के अनुसार इन पदों पर उन्होंने अपने कई वफादारों को नियुक्त किया. इस समय तक यह साफ हो चला था कि सुंदरजी को सेनाध्यक्ष बनने के लिए तैयार किया जा रहा है. पश्चिमी कमान के प्रमुख के पद पर उनकी नियुक्ति उन्हें भारत के सबसे बड़े और सामरिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र से परिचित कराने के लिए की गई.

जनरल अरुण श्रीधर वैद्य के सेनाध्यक्ष बनाए जाने के बाद सुंदरजी को उपाध्यक्ष के रूप में सेना मुख्यालय में दुबारा लाया गया उनके आलोचकों का कहना है कि इस हैसियत में पहुंचने के बाद ही जोड़तोड़ की उनकी प्रतिभा उजागर हुई. उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर ली जिससे दूसरी सेवाओं—तोपखाना और सेना आपूर्ति कोर—के महानिदेशक भी सीधे उन्हें अपनी रिपोर्ट देने लगे.

लेकिन फरवरी 1986 में सेनाध्यक्ष बनने के बाद ही सुंदरजी की महत्वाकांक्षा, प्रेरित

बातचीत

'बदलाव असुविधाजनक ही होता है'

उनकी चाहे कितनी ही आलोचना की जाती रही हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उन जैसे चमत्कारी व्यक्तित्व और बौद्धिक सूझबूझ वाला व्यक्ति सेनाध्यक्ष के पद पर पहले नहीं आया. यह विडंबना ही लगती है कि पिछले सप्ताह जनरल के. सुंदरजी चुपचाप रिटायर हो गए. लेकिन यह उनके साहस और दृढ़-निश्चय का ही प्रतीक है कि सिख उग्रवादियों और तमिल मुक्ति चीतों की हिट लिस्ट में होने के बावजूद उन्होंने, जैसा कि बताया जाता है, राज्यपाल या राजदूत बनने से इनकार कर दिया. सुंदरजी आत्मविश्वास से भरपूर ऐसे व्यक्ति नजर आते हैं, जिसे अपनी योग्यता पर पूरा भरोसा हो. पदमुक्त होने से ठीक पहले ***इंद्रजीत बधवार*** *और* ***दिलीप बॉब*** *से दो टूक बातचीत में सुंदरजी ने अपने कार्यकाल के विवादास्पद पहलुओं और अपनी भूमिका का बचाव वैसे ही आत्मविश्वास से किया जिसके लिए वे चर्चित रहे हैं. बातचीत के अंश:*

● *आपको इस बात की संतुष्टि है कि आप जो कुछ करना चाहते थे, कर पाए?*

जब आप अपने सामने ऊंचे उद्देश्य रखते हैं तो पूर्ण सफलता की उम्मीद रखना बेमानी ही है. कुछ मामलों में हमें कामयाबी नहीं मिली लेकिन उसकी वजह यह नहीं थी कि उसके लिए प्रयास नहीं किया गया. मेरी कोशिश यही रही कि योजनाएं कुछ तो आगे बढ़ें. लेकिन दूरगामी सोच की योजनाओं तक को स्वीकृति प्रदान करने के लिए भी सरकार के पास कोई ढांचा नहीं है.

● *आपका कार्यकाल विवादास्पद रहा है. आपके प्रशंसकों का कहना है कि आप में दूरदर्शिता और नैतिक साहस खूब है जबकि कुछ लोगों का आरोप है कि आप अत्यधिक महत्वाकांक्षी हैं और आप पर फील्ड मार्शल बनने का भूत सवार था?*

हां, गैर-विवादास्पद, रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन होकर भी रहा जा सकता है. बदलाव हमेशा असुविधाजनक ही होता है. मैंने जो कुछ किया, अपनी मान्यताओं के अनुकूल ही किया.

● *क्या वह सब जल्दबाजी नहीं थी?*

परिवर्तन के लिए जोर तो लगाना ही पड़ता है. मुझे छत तक पहुंचने के लिए चांद पर पहुंचने का लक्ष्य सामने रखना पड़ा था.

● *आपके बारे में कहा जाता है कि आप सैन्यतंत्र और प्रशासन के उबाऊपन में उलझने के बजाय दांवपेचों में ज्यादा दिलचस्पी लेते रहे?*

यह गलत धारणा इसलिए बनी कि ज्यादातर युद्धाभ्यास लोगों का ध्यान खींचने वाले थे. इससे यह मान लिया गया कि हम दूसरे पहलुओं की उपेक्षा कर रहे हैं. सैन्यतंत्र को दुरुस्त करने के लिए हमने और लोगों के मुकाबले कहीं अधिक योगदान दिया है.

● *लेकिन इन युद्धाभ्यासों के कारण क्या शस्त्रों की भारी टूट-फूट नहीं हुई?*

नहीं, बिलकुल नहीं. बल्कि सैन्याभ्यास के तुरंत बाद ये अस्त्र-शस्त्र पूरी तरह दुरुस्त कर दिए गए.

● *लेकिन क्या उत्तर-पूर्व में 'ऑपरेशन फाल्कन' के दौरान आपने सेना पर बर्दाश्त से अधिक दबाव नहीं डाल दिया?*

नहीं, ऐसी बात नहीं. यह युद्धाभ्यास तो चीन के मुकाबले अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किया गया था. हम ऐसा धीरे-धीरे भी कर सकते थे. लेकिन हमें डर था कि कुछ स्थानों पर हमारी अपेक्षाकृत कमजोर सुरक्षा व्यवस्था का चीन नाजायज लाभ उठा सकता है. इसीलिए हमने निषेधात्मक रवैया अख्तियार किया.

● *क्या 'ऑपरेशन ट्राइडेंट' का उद्देश्य स्कर्दू को जीतना था? इससे घबराए जनरल जिया ने जब सिंध से दो डिवीजनें पंजाब में भेज दीं तो क्या इसी कारण आपकी वह योजना अधूरी ही रह गई?*

हमारी प्रतिरक्षा की रणनीति निषेधात्मक है. इसका दूसरा महत्वपूर्ण पहलू अनुकूल समय और स्थान पर जवाबी हमला करना है. मुंहतोड़ जवाब देने की हमारे यही क्षमता ही दुश्मन को हमला करने से निरुत्साहित करती है. इस क्षमता का कई बार प्रदर्शन भी करना पड़ता है.

● *क्या यह सफल रहा?*

ऐसी रणनीति कब सफल होगी इसके

> **"गैर-विवादास्पद, रंगहीन, गंधहीन होकर भी रहा जा सकता है... जो किया, अपनी मान्यताओं के अनुकूल किया"**

बारे में कुछ कहना मुश्किल हो जाता है. पंजाब में पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया इसकी वजह यह भी हो सकती है कि वह शायद कुछ करना ही नहीं चाहता था और यह भी कि हमारे रुख को देखकर उसने हिम्मत ही नहीं की. जहां तक खौफ फैलाने की बात है, मैं इससे सहमत नहीं हूं. उसने तो 'ब्रासटैक्स ऑपरेशन' शुरू होने से बहुत पहले ही (अक्तूबर 1986) हमारी टुकड़ियों के वहां पहुंचने का प्रचार करना शुरू कर दिया था. यह जानने के बाद भी कि पाकिस्तान ने अपना युद्धाभ्यास पूरा कर लिया है और उसके सैनिक दस्ते शांति क्षेत्र में नहीं लौटे हैं, हमने आक्रामक रवैया नहीं अपनाया. हमने सीमावर्ती चौकियों पर तभी सैनिक भेजे जब हमें पाकिस्तान के इरादे संदिग्ध लगे. और इरादे तो रातोरात भी बदल सकते हैं. इसलिए उस समय रक्षात्मक रवैया न अपनाना मूर्खता ही होती.

● *क्या अरुण सिंह से आपके घनिष्ठ संबंधों की वजह से सेना के दूसरे अंगों*

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

करने और अपनी बात मनवा लेने की उनकी क्षमताओं ने बड़े नाटकीय ढंग से अपना असर दिखाना शुरू किया. उनके व्यक्तित्व के सर्वाधिक दर्शनीय पहलुओं—प्रस्तुतीकरण के उनके चतुराईभरे अंदाज, उनकी तड़क-भड़क, उनके आकर्षक शब्दजाल (जिसमें युद्ध को चरम पर ले जाने, भेदने की क्षमता, आगे की ओर कूच जैसे अनोखे शब्द शामिल थे) और उनकी बहुत ही आधुनिक सामरिक सोच ने उन्हें तब के सुरक्षा राज्यमंत्री अरुण सिंह और प्रधानमंत्री राजीव गांधी का प्रियपात्र बना दिया था. इस सबके साथ सुंदरजी की उच्च तकनीक पर आधारित सोच तो सोने में सुहागा थी: रणनीति और फौज के स्तर पर कंप्यूटरों के जरिये नक्शों का प्रदर्शन ये सब ऐसी चीजें थीं जिससे राजीव और अरुण सिंह दोनों ही काफी प्रभावित थे.

भारत के प्रतिरक्षा परिदृश्य पर 'इंडिया टुडे' को मिले एक गोपनीय अध्ययन के मुताबिक, "1971 के भारत-पाक युद्ध से ठीक पहले के समय के अलावा भारतीय सेना

विशेषकर वायुसेना को नुकसान नहीं उठाना पड़ा?

यह सच नहीं है. अब से पहले कभी भी सेना के तीनों अंगों ने इस तरह एकजुट होकर काम नहीं किया था. यहां तक कि एअर एविएशन कॉर्प्स के गठन के समय भी किसी किस्म के मतभेद नहीं उभरे.

• 'ब्रासटैक्स' के दौरान और कई योजनाओं को लागू करने में आप कई गलतियों के बावजूद क्या इसलिए छूट गए कि अरुण सिंह के साथ आपके घनिष्ठ संबंध थे?

यह तो सारे मामले को बहुत सरल बनाकर पेश करना हुआ. प्रतिरक्षा मामलों में वे गहरी रुचि लेते थे. वे समस्याओं को अपेक्षाकृत जल्दी और गहराई तक समझते थे. ऐसे व्यक्ति से सामंजस्य बिठाना निश्चय ही सहज तो होता है लेकिन वे कोई काम मुझे इसलिए नहीं करते थे कि सुंदरजी ने ऐसा कहा है.

• धारणा है कि आपने जीसीओ (सामान्य श्रेणी अधिकारी) में से किसी अफसर को अपने प्रिंसिपल स्टॉफ अफसर के रूप में नियुक्त न करके उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया है.

मैं योग्यता के आधार पर ही व्यक्ति का चुनाव करता हूं. इससे उन लोगों का नाराज होना स्वाभाविक ही है जो विशेषाधिकार प्राप्त किए हुए हैं.

• लेकिन अब सेना में उच्च स्तर के अधिकारियों की भरमार है. अफसरों को तरक्की देने की धुन में आपने ज्यादा लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल और ब्रिगेडियर बना दिए और इस तरह उनका पदमान ही घटा दिया.

भवान सिंह

कबूल करता हूं. पदावली का ढांचा सरल बनाना और यूनिट कमांडर की परिकल्पना को फिर से लागू करना जरूरी है. मुझे यूनिट कमांडर बनने वाले अधिकारियों की उम्र की भी चिंता रही है. आज 40 वर्ष की आयु के बाद यूनिट कमांडर बन पाते हैं, जबकि 30 वर्ष की उम्र में ही यह पद मिल जाना चाहिए.

• क्या आपको लगता है कि श्रीलंका में शांति स्थापना की प्रतिबद्धता के कारण सेना ने खुद पर बहुत ज्यादा बोझ डाल लिया है और इस तरह देश को नाजुक स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है?

हां, यह सही है कि सेना पर दबाव बढ़ा है. लेकिन देश को नाजुक हालत में ला खड़ा करने की बात सही नहीं.

• 'ऑपरेशन पवन' का कार्यरूप देने में क्या आपको और वक्त नहीं लेना चाहिए था. जैसा कि मानेकशॉ ने 1971 में बांग्ला देश अभियान में किया था?

1971 में आप और वक्त मांगने की बात सोच सकते थे लेकिन 'ऑपरेशन पवन' महज एक सैनिक कार्रवाई नहीं बल्कि राजनैतिक-सैन्य अभियान भी था.

• क्या खुफियातंत्र नाकाम हो गया था?

हथियारों से संबंधित सूचनाएं तो मिलीं पर उग्रवादियों के मनोबल और मोर्चे पर डटे रहने की उनकी क्षमता के बारे में मिली सूचनाएं पर्याप्त नहीं थीं.

• आप ही अकेले ऐसे व्यक्ति थे, जो राजनैतिक नतीजों के मद्देनजर ऑपरेशन ब्लूस्टार के लिए इनकार कर सकते थे. लेकिन आपने ऐसा नहीं किया. क्या इसका कोई कम पीड़ादायक विकल्प नहीं था?

काफी सोच-विचार कर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि यह उचित था. यदि इसको लेकर मेरे मन में कोई शंका होती तो एक अच्छा सैनिक होने के नाते मैंने तत्काल इस्तीफा दे दिया होता.

• अपने सैनिकों से सीधा संपर्क न रखने; सामान्य सैनिकों तक पहुंचकर उनका हाल-चाल न पूछने और मानवीय संवेदना प्रदर्शित न करने के लिए आपकी आलोचना होती है.

मैं मानता हूं कि मैंने मैदान के मुकाबले ज्यादा वक्त मुख्यालय में ही बिताया है. लेकिन यह सोच-समझ कर किया गया फैसला था. मैं जो तब्दीलियां करना चाहता था उनके लिए मेरा ज्यादा समय मुख्यालय में रहना जरूरी था.

• अब जबकि आप पदमुक्त हो रहे हैं, भारत की सुरक्षा तैयारी को आप कैसा आंकते हैं?

चीन के मुकाबले तो हम निश्चित ही पहले से ज्यादा तैयार हैं. पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की क्षमता भी हममें है. लेकिन ज्यादा खतरा चीन से ही है. पाकिस्तान से तो हम यों ही निबट लेंगे.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अगर आप सोचते हैं कि साधारण बीमाकर्मी इतने मुश्किल से मिलते हैं...

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सोचिए नेशनल परिवर्तन के लिए

नेशनल को आपके महत्व का एहसास है, जब भी आपको हमारी सेवा की आवश्यकता होगी, हम हमेशा तैयार मिलेंगे ।

पिछले वर्ष हमने जो तीन लाख पचास हजार से भी अधिक ग्राहकों के दावों को तुरंत निपटा दिया-वही इस बात को प्रमाणित करेंगे, जिसका मतलब है सहज उपलब्धता ।

जब भी आप साधारण बीमा के लिए हमारे पास आयेंगे । हम आपके आसपास ही मिलेंगे । यही से हमारी सेवा का आरंभ होता है ।

प्रतिदिन हमारे आफिसों का जाल देश में आश्चर्यजनक ढंग से बढ़ रहा है ताकि हम आपके निकट सहजतापूर्वक पहुंच सकें ।

पिलीभीत की वर्फीली चोटियों से लेकर 'टूरा' के दहकते जंगलों तक हम आपकी सेवा के लिए हमेशा तैयार मिलेंगे ।

हमारी सारी पालिसियां आप की सभी प्रकार की क्षति की पूर्ति करने में सक्षम हैं, जैसे मवेशियों से लेकर कम्प्यूटर और कृषि से विमानन तक ।

हमारे पेशेवर दल, जैसे वेटनरी सर्जन, कम्प्यूटर एनालिस्ट्स और इंज़ीनियर आदि हमेशा आला दर्जे की सेवा के लिए तैयार मिलेंगे ।

इस में कोई आश्चर्य नहीं कि
अब अधिकाधिक लोग नेशनल के संबंध में ही सोचने लगे हैं ।

इस का अर्थ होता है आरंभ से अंत तक उत्तम सेवा ।

सोचिए नेशनल बीमा सुरक्षा के लिए

नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

(भारतीय साधारण बीमा निगम की सहायक कंपनी)

TSAC-NIC-2

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पीआईबी

जाफना में कमांडरों के साथ

और राजनैतिक नेतृत्व में शायद ही कभी इतनी गहरी छनी हो. शक्ति प्रदर्शन के लिए दिल्ली की निर्भीक पहल, उसकी नई कूट-नैतिक आक्रामकता और उसके जोशीले आत्मविश्वास का सुंदरजी द्वारा राजनैतिक आलाकमान से स्थापित किए गए नए संपर्कों से गहरा संबंध था."

इसका सबूत ऑपरेशन ब्रासटैक्स और उससे संबंधित युद्धाभ्यासों के दौरान मिला. चार चरणों का यह युद्धाभ्यास 1986-87 की सर्दियों में राजस्थान के रेगिस्तान में हुआ और भूमि पर हुए दुनिया के अब तक के युद्धाभ्यासों में सबसे बड़ा था. इस अभ्यास में शामिल कई वरिष्ठ सैनिक अधिकारियों के मुताबिक ब्रासटैक्स का जाहिरा मकसद सुंदरजी के सामरिक सिद्धांतों का परीक्षण ही था. इस अभियान के तहत मैक्नाइज्ड युद्ध, सेना को मिले नए हथियारों, थलसेना को वायुसेना के घनिष्ठ सहयोग और बख्तरबंद गाड़ियों की बड़े पैमाने पर कूच का परीक्षण किया गया. इस बहुआयामी सैनिक अभ्यास में 2400 टैंकों ने हिस्सा लिया था.

पर ब्रासटैक्स की वजह से पाकिस्तान से दो-दो हाथ होने की नौबत भी आ गई क्योंकि उसकी सीमा के बिलकुल नजदीक हुए इस अभ्यास में भारी तादाद में फौजें शामिल थीं. इस बात में कोई शक नहीं कि ब्रासटैक्स ने जमीन पर होने वाली लड़ाई के प्रति सुंदरजी की कुछ धारणाओं को तो सच ही साबित किया. मसलन—बख्तरबंद गाड़ियों (टैंक आदि) की तेजी से हल-चल, लड़ाई के वक्त उम्दा खुफियातंत्र की उपल-ब्धता, एमआई-17 और एमआई-25 हमलावर हेलिकॉप्टरों के सहयोग के रूप में थलसेना की बल-वृद्धि और निषेधात्मक और निवारक रुख अपनाने के सुंदरजी के व्यापक नजरिये की कामयाबी.

राजनीतिकों पर असर डालने के लिए जल्दबाजी में कार्रवाइयां करना सुंदरजी की आदत रही है. श्रीलंका में ऑपरेशन पवन इसी की मिसाल है

हालांकि राजनयिक और वास्तविक सैनिक दृष्टिकोण से देखें तो ब्रासटैक्स का असर एक तरह से विनाशकारी ही रहा. रक्षा मंत्रालय के आला सूत्रों के मुताबिक सुंदरजी ने अरुण सिंह को यकीन दिला दिया था कि धौंस-डपट की कूटनीति के उनके सिद्धांत को जाहिर करने के लिए ब्रॉसटैक्स निहायत जरूरी है. दूसरे शब्दों में, पाकिस्तान को इशारा कर दिया जाए कि अपने राष्ट्रीय हित में हमला बोलने की भारत न केवल इच्छाशक्ति रखता है बल्कि उतनी ताकत भी उसके पास है.

सैनिक मुख्यालय के लिए तैयार की गई एक गोपनीय रिपोर्ट के मुताबिक "लड़ाई से पहले के राजनैतिक और सैनिक मूल्यांकन से लेकर कमांड स्तर के इस युद्धाभ्यास (ब्रास-टैक्स) तक का मकसद हमेशा त्यौरियां चढ़ाए रखने वाले उद्दंड पड़ोसी को भारत की सैनिक ताकत का एहसास करा देना था."

कुछ स्पष्ट कारणों से यह रिपोर्ट सुंदरजी की योजना के वास्तविक इरादों का पूरी तरह खुलासा नहीं करती. पर रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इस योजना का मकसद था पाकिस्तान को कोई कार्रवाई करने के लिए उकसा देना जिससे भारतीय सेना को हमला करने का बहाना मिल जाता. इस आक्रामक अभियान का सांकेतिक नाम था—ऑपरेशन ट्राइडेंट. प्रति-रक्षा विश्लेषक रवि रिखी की आने वाली किताब के मुताबिक "ट्राइडेंट उस हमले की तैयारी थी जिसका पहला निशाना पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर का इलाका स्कर्दू और दूसरा निशाना गिलगित था."

रिखी लिखते हैं, "ब्रासटैक्स का असल मकसद साम-रिक तौर पर बड़ा धोखा देना था जिससे पाकिस्तान का ध्यान सिंध में बंट जाए और जबकि भारत उत्तर की ओर बढ़ जाए." पर वरिष्ठ कमांडरों के मुता-बिक समस्या यह हो गई कि पाकिस्तान ने अपना युद्धाभ्यास जारी रखा और उसकी सेना हरकत में रही. यही वजह थी कि युद्ध का अनुकूल खौफ पैदा करने की अरुण सिंह और सुंदरजी की शुरुआती कोशिशें नाकामयाब हो गईं. 18 दिसंबर 1987 को सुंदरजी और अरुण सिंह ने राष्ट्रीय अखबारों के संपादकों को इस बारे में जो विस्तृत ब्यौरा दिया उसका आशय यही था कि सीमा पर सेना लगाने की पहल पाकिस्तान ने ही की और देश को बुरे दिनों के लिए तैयार हो जाना चाहिए.

इस ब्यौरे पर विदेश मंत्रालय ने कड़ा विरोध जताया क्योंकि उसे इस बारे में पूरी जानकारी नहीं दी गई थी. एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री ने बाद में 'इंडिया टुडे' को बताया, "मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस आदमी (सुंदरजी) ने हमें करीब-करीब युद्ध में ही झोंक दिया था. यहां तक कि प्रधानमंत्री को भी पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई." भारत ने तनाव घटाने और पीछे हटने का फैसला तभी किया जब रूसी और अमे-रिकी राजदूतों ने विदेश मंत्रालय को सूचित किया कि उनकी खुफिया जानकारी के मुता-बिक पाकिस्तान की नीयत में खोट नहीं है.

ऑपरेशन ब्रासटैक्स ही अकेला ऐसा अभियान नहीं था जिसकी वजह से इस्लामा-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बाद, वाशिंगटन, मास्को और यहां तक कि पेइचिंग में भी चिंता व्याप्त हो गई थी. पूर्वी क्षेत्र में एक और अभ्यास किया गया जिसका नाम था—ऑपरेशन चैकरबोर्ड. इसका विस्तार था—ऑपरेशन फॉल्कन. इसमें शामिल सेना की तीन डिवीजनें अरुणाचल प्रदेश के वानडंग के इर्द-गिर्द के मोर्चों पर पहुंच गई थीं. इसी के साथ वर्तमान सड़कों से 80 किमी आगे तक हवाई जहाजों में लादकर 1000 टन के उपकरण भी पहुंचा दिए गए थे. इस अभियान में शामिल एक वरिष्ठ कमांडर के मुताबिक, "हमने हवाई सहायता को छोड़कर बगैर किसी सैनिक मदद के चीन से लगभग लड़ने की ही कोशिश कर डाली."

पर सुंदरजी के हिमायती कहते हैं कि युद्ध के कगार पर पहुंचा देने के लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता और राजनैतिक नेतृत्व ने ही उन्हें आक्रामक रुख अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया. गोपनीय रिपोर्ट कहती है, "राजनैतिक पहल के जरिये भारत की ताकत दिखाने की मंशा इस वजह से बढ़ गई कि सुंदरजी में इसे सैनिक उद्देश्यों में तब्दील करने की काबिलियत थी." पर कूटनीतिक नजरिये से देखें तो नई दिल्ली का चेहरा ही कीचड़ में सना.

ब्रासटैक्स के चलते ही सुंदरजी पर से राजनैतिक वरदहस्त उठ गया. यही वह समय था जब राजीव और अरुण सिंह के रिश्तों में खटास आने लगी थी. पर ब्रासटैक्स से सेना को कई गंभीर सबक मिले और सुंदरजी के युद्ध सिद्धांतों की खामियां सामने में आने लगीं. एक कोर कमांडर का कहना है, "ब्रासटैक्स का युद्ध सिद्धांत सन् 2000 के लिए था, अभी इसकी जरूरत नहीं है. जमीन और आकाश से एक साथ युद्ध, हर रोज नौ घंटे भागते-दौड़ते टैंकों के साथ हवाई हमलावर दस्तों को लगाने जैसे एकीकृत सिद्धांतों पर अमल करना हमारी मौजूदा सामर्थ्य में नहीं है. यह हो सकता है कि ब्रासटैक्स से कुछ सैनिकों को अपनी मौजूदा ताकत और दमखम दिखाने का मौका मिला हो और इससे उनमें अभिमान का भाव आया हो. पर इससे बड़ी तादाद में असले को नुकसान पहुंचा."

बख्तरबंद कोर के अफसरों के मुताबिक रेगिस्तान में लंबी दूरियां तेजी से तय करने के कारण टैंकों के इंजिन, ट्रैक्स और दूसरे कलपुर्जों को भारी नुकसान पहुंचा. जबसे सुंदरजी ने बख्तरबंद दस्ते की अगुआई संभाली, बख्तरबंद कोर के अधिकारी उनकी काबिलियत पर ही सवाल उठाते रहे हैं. इससे भी उनमें अपने को सही साबित करने की इच्छा बलवती होती गई. बख्तरबंद कोर के एक वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं, "अपनी काबिलियत की आलोचनाओं का जवाब देने के लिए उन्होंने काफी समय तो लामबंदी के अध्ययन में बिताया, वे रात-रात भर टैंक चलाते थे, उससे गोले दागते थे और तकरीबन 90 डिग्री तक ऊंचे टीलों पर टैंक चढ़ा देते थे. बहादुरी की ऐसी ही धारणाओं को उन्होंने ब्रासटैक्स जैसे सैनिक अभ्यासों में शामिल कर लिया."

सुंदरजी का राजनैतिक रसूख भले ही खत्म हो गया पर उनकी विरासत साउथ ब्लॉक में गहरे जम गई है. यह बात न सिर्फ सियाचिन में जारी झड़पों से जाहिर होती है बल्कि ऑपरेशन चैकरबोर्ड और ऑपरेशन फॉल्कन के दौरान चीन के खिलाफ अपनाए गए हमलावर तेवर से भी पता लगती है. विदेश नीति में जाहिर हो रहे अंतर्विरोधों की वजह से यह रवैया कुछ मद्धिम पड़ा. ब्रासटैक्स तब हुआ जब पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की कोशिश चल रही है, चैकरबोर्ड व फॉल्कन तब हुए जब चीन से सीमावार्ता का सातवां दौर चल रहा था और कोई एकमुश्त समझौता तैयार किया जा रहा था. सैनिक मुख्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं, "हमने चीन को पूर्वोत्तर में ज्यादा कड़ा और युद्धोन्मुख रवैया अपनाने के लिए मजबूर कर दिया. अब राजनैतिक नेतृत्व राजीव की प्रस्तावित पेइचिंग यात्रा से उसके इस रवैये को शांत करने की कोशिश में लगा हुआ है."

इससे फिर यही जाहिर होता है कि सुंदरजी किस कदर राजनैतिक नेतृत्व पर हावी हो गए थे. सुंदरजी के सारे तर्क इस दावे पर आधारित हैं कि भारत एक साथ ही चीन और पाकिस्तान दोनों से भिड़ सकता है. राजनैतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की जिस बैठक में उन्होंने अपना यह सिद्धांत पेश किया उसमें एक कैबिनेट मंत्री ने मजबूर होकर उन्हें यह चेतावनी दी थी, "अपने दो ताकतवर पड़ोसियों से भिड़ने की ये युद्ध-पिपासु बातें हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगी." लेफ्टिनेंट जनरल थॉमस कहते हैं, "मुझे नहीं लगता कि चीन और पाकिस्तान से भिड़ने की इन बातों का कोई फलदायी नतीजा निकलेगा. पाकिस्तान पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है. हमारी सेना का फैलाव ज्यादा है और पंजाब पहले की तरह अभियान

सुंदरजी ने राजनैतिक नेतृत्व को यकीन दिला दिया था कि धौंस-डपट की कूटनीति, और निवारक क्षमता जाहिर करने के लिए ब्रासटैक्स जरूरी है

ब्रासटैक्स : भारी कवायद

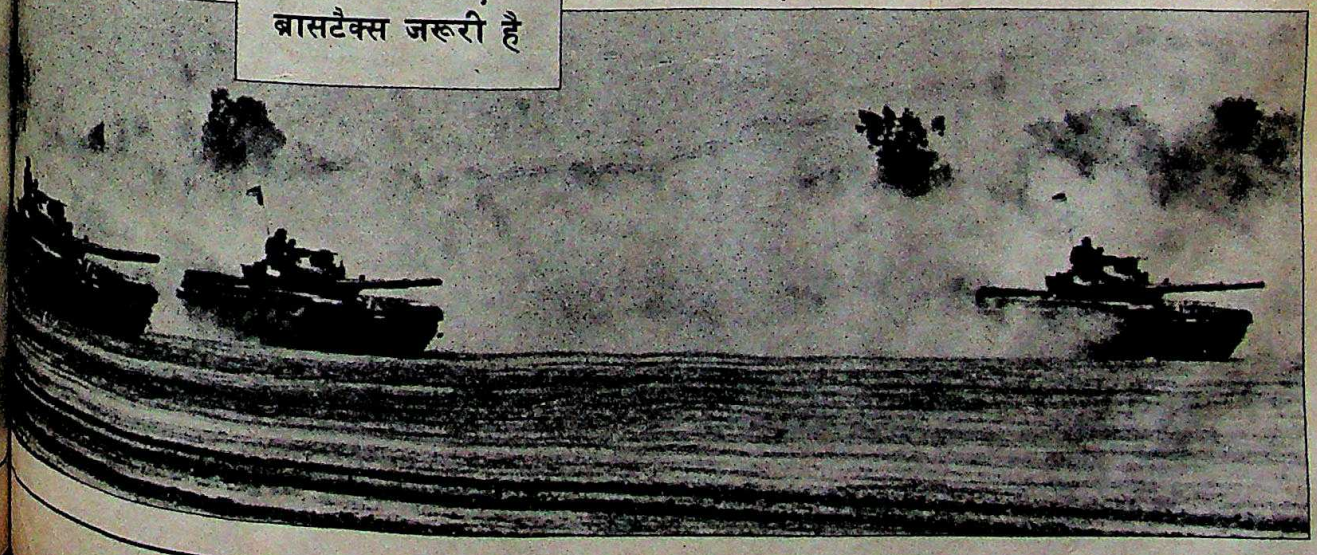

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रघु राय

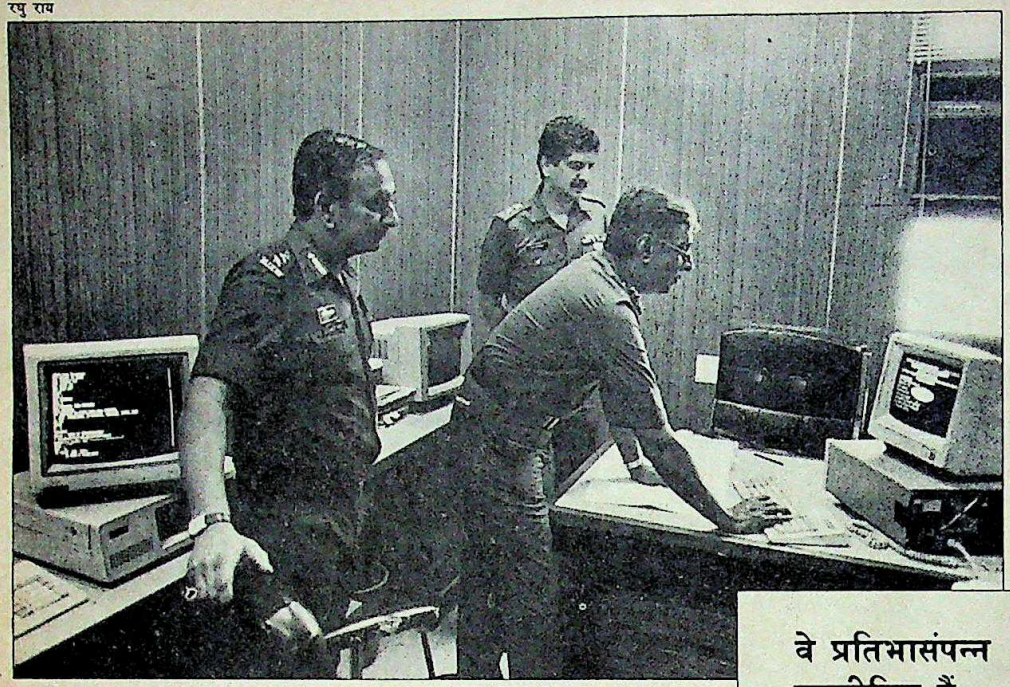

साउथ ब्लॉक में स्टाफ के साथ

चलाने के लिए अब स्थिर आधार (अड्डा) नहीं रह गया है."

असल में सुंदरजी की ज्यादा आलोचना इसी बात को लेकर होती है कि उन्होंने सेना को काफी फैला दिया. खास तौर पर श्रीलंका में, ऑपरेशन पवन के बाद, जिसमें भारतीय सेना की सिर्फ दो असरदार सुरक्षित-36वीं और 54वीं डिवीजनों समेत 80,000 सैनिक उलझा दिए गए, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पश्चिमी कमान के सैनिक दस्तों को श्रीलंका के मोर्चे पर लगा दिया गया.

जैसी कि ज्यादातर अफसर और दूसरे ओहदों के सैनिक अब शिकायत करते हैं, "भारतीय सेना आज एक क्लांत सेना है." सैनिकों को छह-छह महीनों तक उनके मूल अड्डों पर नही भेजा गया. लद्दाख में केवल दो महीने की तैनाती के बाद हाल ही में जयपुर में तैनात किए गए राजपूत रेजीमेंट के एक सूबेदार मेजर कहते हैं, "मेरी बटालियन चुशूल में तैनात है और मैं जयपुर जा रहा हूं और राम जाने मुझे वहां से फिर कितनी जल्दी हटा लिया जाएगा. मैंने लगभग पिछले दो साल से अपने परिवार के सदस्यों की शक्ल तक नहीं देखी है." जाहिर है, चीनियों ने इस तथ्य को गंभीरता से लिया है. और अभी हाल में पेइचिंग से प्रसारित रेडियो प्रचार में, जिसे रक्षा मंत्रालय ने सुना है, कहा जा रहा है कि "1962 में हमारा सामना बिना तैयारी वाली भारतीय सेना से हुआ था और अब हमारे सामने एक थकी हुई भारतीय सेना है."

सियाचिन और श्रीलंका इसकी सबसे बढ़िया मिसाल हैं. हालांकि सियाचिन में सैनिक दस्तों की तैनाती में बदलाव होता रहता है: लेकिन जमा देने वाली ठंड, लड़ाई की कठिन स्थितियां, आपूर्ति की और संचार की समस्याओं और मरने वालों की संख्या (अनुमानत: एक साल में 250) ने मनुष्य के साहस को अविश्वसनीय कसौटी पर कसा है. श्रीलंका भेजने के लिए सैनिक दस्तों को रातोरात जुटाया गया. और वहां पहुंचने के कुछेक घंटों के भीतर ही उन्हें एक ऐसे इलाके की लड़ाई में झोंक दिया गया जिसकी उन्हें बिलकुल जानकारी न थी. सेना के वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं कि श्रीलंका का मामला भी राजनीतिकों को प्रभावित करने के लिए जल्दबाजी में कार्रवाइयां करने की सुंदरजी की आदत का ही एक नमूना है. यह स्पष्ट है कि ऑपरेशन ब्लूस्टार की तरह ही ऑपरेशन पवन भी पर्याप्त खुफिया सूचनाओं के बिना, जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास से प्रेरित होकर किया गया. शत्रु की क्षमता और मनोबल का इसमें भी कोई सही अंदाज नहीं लगाया गया.

हालांकि ऑपरेशन पवन से सुंदरजी को अपनी बहुत-सी रणनीतिक मान्यताओं—पैरा कमांडो दस्तों और हवाई हमला डिवीजन—को कसौटी पर कसने का मौका मिला. लेकिन यह अभियान उम्मीद के अनुरूप तेजी और प्रभावशाली तरीके से संपन्न नहीं हो पाया.

ये अधिकारी सैम मानेकशॉ का उदाहरण देते हैं कि किस तरह उन्होंने 1971 में इंदिरा गांधी से साफ कह दिया था कि पूर्वी पाकिस्तान में कूच करने के लिए तैयार होने में वक्त लगेगा. और श्रीमती गांधी के अनुरोध के एक महीने बाद उन्होंने वहां सेना भेजी. एअर कमोडोर जसजीत सिंह कहते हैं, "इस (श्रीलंका) अभियान में कम खामियां होतीं और यह एक बेहतर अभियान साबित होता यदि इसकी तैयारी में थोड़ा वक्त दिया जाता. लेकिन पता नहीं सुंदरजी किन दबावों या मजबूरियों के अधीन काम कर रहे थे!"

वे प्रतिभासंपन्न रणनीतिज्ञ हैं—आधुनिक विचारों से लैस सेनानायक जिन्होंने सेना को नई दृष्टि दी पर उनकी ज्यादातर धारणाएं युद्धोन्मुख ही रहीं

और यही शायद उनकी सबसे बड़ी खामी है. उनका अहं इतना प्रबल था, उनकी महत्वाकांक्षाएं इतनी ऊंची थी कि ऐसी परिस्थितियों में वे न तो किसी की सलाह लेने को तैयार हो सकते थे और न ही कोई सावधानी बरतने को. और शायद इन्हीं कारणों से सुंदरजी के कामकाज का यथार्थपरक आकलन नहीं हो पाएगा. शायद वे अपने वक्त से आगे के शख्स थे—20वीं शताब्दी की सेना का नेतृत्व कर रहा 21वीं शताब्दी वाला सेनानायक. तभी शायद उनकी कई मान्यताओं की चौतरफा आलोचना हुई. इनमें से कुछ हैं:—

- विस्तृत ब्यौरों, प्रशासनिक और तार्किक तथ्यों के प्रति उनका उपेक्षा भाव. इसकी सबसे बेहतर मिसाल ऑपरेशन ब्रासटैक्स है जिसमें बख्तरबंद दस्ते इतनी तेजी से आगे बढ़ गए कि सहयोगी, पूरक और आपूर्ति दस्ते बहुत पीछे छूट गए.
- सेना के उच्चस्तरीय सांगठनिक पारंपरिक ढांचे में फेरबदल और मोर्चे पर तबादले आदि की नई व्यवस्था से काफी असंतोष पनपा.
- रेजीमेंट के कमांडिंग अफसर (सीओ) के पुराने पद को खत्म करना. इस पद पर लेफ्टिनेंट कर्नल की नियुक्ति होती थी. 'सीओ' वास्तव में जवानों से सीधे जुड़ा होता था और उनके लिए प्रेरक शक्ति होता था. वह हरेक सैनिक को नाम से जानता था और

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

युद्ध के मैदान में वही उनका नेतृत्व करता था. अब ओहदों का रुतबा बढ़ाने की सुंदरजी की व्यवस्था के तहत रेजीमेंट में सीओ के पद पर एक कर्नल और उसके सहायक दो लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं. इस कारण अब तुरतफुरत फैसला लेना संभव नहीं रह गया है और जवाबदेही भी बंट गई है.

• रेगिस्तानी लड़ाई, गतिशीलता और मशीनीकरण के प्रति उनके मोह ने सेना के पैदल सेना को कमजोर कर दिया. सेना मुख्यालय में आज संगठन से जुड़े प्रमुख अधिकारियों—पीएसओ—के पद पर इन्फैंट्री का कोई भी अधिकारी नहीं है.

• ओहदों के पुनर्गठन के कारण अब हो यह गया है पहले जिन पदों पर ब्रिगेडियर होते थे आज लेफ्टिनेंट जनरल विराजमान हैं.

• उनकी प्रबंध व्यवस्था में निचले ओहदों पर ध्यान कम दिया जाता रहा और जोर केवल सामरिक नीतियों वगैरह पर दिया जाता रहा. इस कारण जवानों का मनोबल बढ़ाने वाले महत्वपूर्ण पहलू की हमेशा ही उपेक्षा की जाती रही.

• जिस गति से उन्होंने सेना में उच्च तकनीक लागू करने की कोशिश की वह आम जवानों की पकड़ से ज्यादा ही तेज थी.

काम करने की तूफानी रफ्तार वाले इस दृष्टिकोण के चलते ही शायद सुंदरजी की उपलब्धियां धूमिल लगती हैं. इसमें कोई शक नहीं कि वे एक बेहद प्रतिभासंपन्न रणनीतिज्ञ हैं—आधुनिक विचारों से लैस सेनानायक जिन्होंने सेना को आधुनिक दृष्टि दी.

उनके विचारों का सेना पर गहरा असर पड़ा. उनकी समीक्षा शायद आगे चलकर हो. वे 20वीं सदी की सेना के 21वीं सदी वाले जनरल थे

सीनियर कमोडोर जसजीत सिंह कहते हैं, "सुंदरजी का दृष्टिकोण सही था. वे चाहते थे कि अधिकारी उनसे निस्संकोच बात करें, उन्हें लिखें. लेकिन दूसरे लोग अगर उनके साथ कदम मिलाकर नहीं चल पाए तो उनका क्या कसूर. जो वे चाहते थे साफ-साफ बताते थे. उनकी पहल पर कार्रवाई करना तो अधिकारियों की जिम्मेदारी थी. क्या उनके सोचने के तरीके में कोई खामी थी? या वे लोगों को प्रोत्साहित नहीं कर पाते थे?"

इसका शायद सबसे बढ़िया जवाब सुंदरजी के आलोचक रहे एक कोर कमांडर ने दिया, "उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह है कि उन्होंने उपयोगी प्रासंगिक अध्ययन-मनन को बढ़ावा दिया. 25 वर्षों बाद सेना को किन साधनों या साजो-सामान की जरूरत पड़ सकती है, इस बारे में सोच-विचार की शुरुआत कराई. दो वर्षों में यह अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि है. दूसरा कोई सेनाध्यक्ष ऐसा नहीं कर पाता. हालांकि उन्होंने सन् 2,000 के बारे में सोचने की शुरुआत कराई. लेकिन आज की परिस्थितियों में कल की योजनाओं को लागू करने की जद्दोजहद से उलझन बढ़ गई."

बहरहाल, सुंदरजी की उपलब्धियों का उनके कार्यकाल की चुनौतियों और संयोगों के संदर्भ में ही आकलन किया जाना चाहिए. वे राजीव के प्रधानमंत्री बनने के कुछ ही समय बाद सेनाध्यक्ष बने. उस समय उच्च तकनीक और कंप्यूटर का हौवा अपनी पराकाष्ठा पर था. राजीव और अरुण सिंह की तरह, सुंदरजी भी आधुनिक विचारों वाले व्यक्ति हैं. इसी कारण आधुनिकीकरण की सारी योजनाएं वे लागू करवाने में सफल रहे.

विचारों के साम्य के कारण राजनीतिकों पर उनकी जैसी पकड़ रही वैसी दूसरे किसी सेनाध्यक्ष की नहीं रही. लेकिन इसे नजरअंदाज भी कर दें तो भी पूर्ववर्ती सेनाध्यक्ष—चाहे वे ए.एस. वैद्य हों या कृष्णाराव या टी.एन. रैना और यहां तक मानेकशॉ भी सेना के पारंपरिक ढांचे से छेड़छाड़ की हिम्मत नहीं जुटा पाए. और न ही उनके पास सुंदरजी जैसी आधुनिक परिष्कृत सामरिक दृष्टि थी. तभी तो आज भारतीय सेना परिवर्तन के दौर में है. अगले 15 वर्षों में तकनीक के मामले में इसका पूरी तरह पुनर्गठन हो जाएगा और सैनिकों को सुंदरजी की परिकल्पना के मुताबिक प्रशिक्षित कर दिया जाएगा. लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि परिवर्तन के इस दौर में या आगामी दस वर्षों में सेना उस युद्ध का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं कर सकती जिसकी परिकल्पना सुंदरजी करते रहे हैं.

—इंद्रजीत बधवार और दिलीप बॉब

भवान सिंह

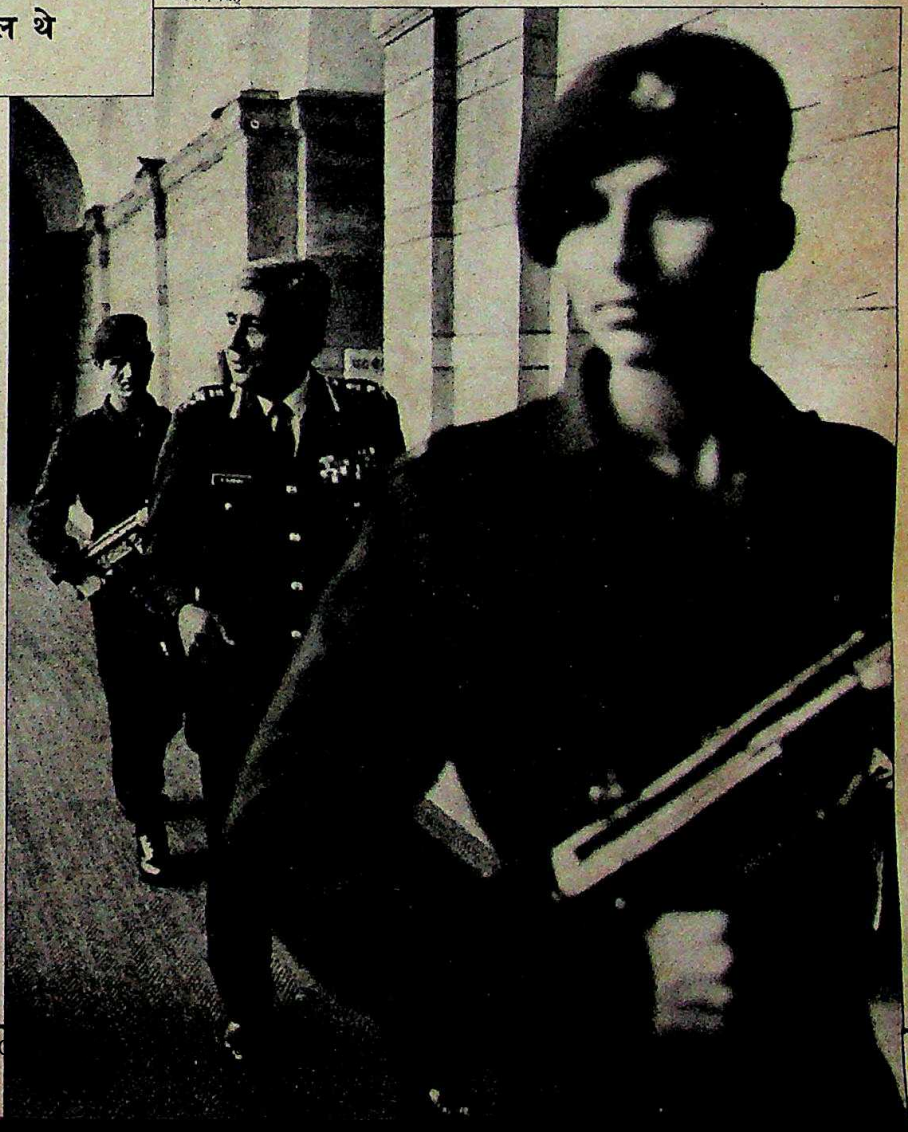

रफ्तार में सुरक्षा के इंतजाम

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जो देश में लोकप्रिय हो, उसे नैशनल कहते होंगे– आप चुनिये वो – जो इन्टरनैशनल है!

अकाइ VS-23

केवल अकाइ में इतने सारे गुण AKAI

क्विक स्टार्ट (प्ले और रेकार्ड)
बस बटन दबा और तस्वीर तुरन्त उभरी केवल डेढ़ सेकन्ड में! अन्य वी.सी.आर. पर इसमें लगते हैं ८ सेकन्ड।

क्विक इन्डेक्स सर्च
जो कार्यक्रम आप देखना चाहें, यह उसी को शुरू से लगाये। ढूंढते रहने की ज़रूरत नहीं।

क्विक इन्ट्रो स्कैन
तलाश के तुक्के लगाना बन्द। इन्डेक्स सिग्नल वाले कार्यक्रम के प्रथम भाग ८ सेकन्ड तक दिखाकर, ये चुनाव में मदद करे।

इन्टर एक्टिव मॉनिटर सिस्टम
किस काम के लिये कौनसा बटन दबाना, यह स्क्रीन पर बताये।

सुपर क्लियर स्लो मोशन
टेप चलाने की गति को कम करने से, यह मनचाहा दृश्य स्लो मोशन में भी साफ़ दिखाये।

डबल स्पीड प्लेबैक
टेप का मनचाहा हिस्सा ढूंढने के लिये दुगनी स्पीड का प्रबन्ध।

सुपर स्टिल
चलचित्र को स्थिर कर दीजिये। या एक एक फ्रेम आगे बढ़ाइये।

हाई क्वालिटी सिस्टम
एच. क्यू. सिस्टम द्वारा चित्र बहुत साफ़ दिखाये, हर बारीकी निखारे। "CCD नॉइज़ कैन्सलर" ध्वनि से शोर मिटाये।

इलेक्ट्रॉनिक चाइल्ड लॉक सिस्टम
बच्चों को उन कार्यक्रमों से बचाये रखे जो उनके देखने योग्य नहीं।

10-की वायरलेस रिमोट
अनुपम १० बटनों वाला रिमोट कन्ट्रोल-टाइमर प्रोग्रैमिंग से लेकर ट्रैकिंग तक हर काम करे।

4 प्रोग्रॉम 1 महीना टाइमर
आपकी पसन्द के टी.वी. कार्यक्रम अपने आप नियुक्त समय पर रेकॉर्ड करे।

युनीक टेप व्यू सिस्टम
चलता हुआ टेप दिखाई देने का प्रबन्ध, जिससे आप ठीक से जान सकें कि कितना टेप बचा है।

मेमरी बैक-अप
बैटरी बैक-अप सिस्टम, पावर फ़ेल हो जाने पर भी एक घन्टे तक मेमरी सुरक्षित रखे

अन्य गुण
62 टी.वी. प्रीसेट स्टेशन, क्विक टाइमर, ऑटो पावर ऑन, ऑटो प्ले, ऑटो रिजेक्ट, ऑटो रिवाइन्ड, पावर ऑफ़ इजेक्ट, ऑटो काउन्टर डिस्प्ले, ऑटो डिमर क्लॉक।

मुफ़्त वारन्टी
अकाइ एक्विपमेन्ट यू.ए.ई. में ख़रीदने पर साथमें यह वारन्टी कार्ड मुफ़्त मिलेगा। यह कार्ड इस बात की गारन्टी है कि भारत, इजिप्त, जॉर्डन, पाकिस्तान, फिलिपीन्स, सिरिया और थाइलैन्ड में बढ़िया सर्विस भी मिलेगी, और पुर्ज़े भी मुफ़्त बदले जासकेंगे।

GENERAL ENTERPRISES CO.
P.O. Box 363, Dubai, U.A.E., Tel: 224131, 236575,
Tlx: 45528 GECO EM, Fax: 281703

GECO
जीको के वादे से सशक्त।
क्वालिटी का वादा–
सर्विस का वादा।

INCA/AK/249

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पंजाब

खतरों से घिरे खबरनवीस

आतंकवादी और पुलिस दोनों के ही कहर के शिकार

पंजाब में आतंकवादियों के पास जहां घातक हथियारों का जखीरा है और सरकार के पास मनमाने अधिकारों का भंडार, वहीं पत्रकारों के पास ढेरों धमकी भरे पत्र जमा हो गए हैं. पर उन्हें खतरा इन पत्र लिखने वाले आतंकवादियों से ही नहीं, सरकार की ओर से भी है.

यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया (यूएनआई) के अमृतसर संवाददाता कुलदीप सिंह अरोड़ा को 13 अप्रैल को टेलर रोड के उनके निवास और कार्यालय से गिरफ्तार करके शहर के बदनाम पूछताछ केंद्र में ले जाया गया. बाद में उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जिला जेल भेज दिया गया.

अरोड़ा पर लगाए गए आरोपों से पत्रकार बहुत खफा हैं. उन्हें स्वर्ण मंदिर में आतंकवादियों से मुलाकात करने का दोषी ठहराया गया है. यह नए आतंकवाद विरोधी कानून के तहत गंभीर आरोप है. यदि कानून इसी तरह सख्ती से लागू किया जाता रहा तो करीब 100 पत्रकार इसकी ज़द में आ जाएंगे. अमृतसर श्रमजीवी पत्रकार संघ के महासचिव शम्मी सरीन कहते हैं, "यह तो हमारे नाम सरकार का खुला संदेश है कि ऐसा कुछ न लिखें जो अधिकारियों को अरुचिकर लगे."

लेकिन नाम न छापने की शर्त पर पुलिस के उच्चस्तरीय सूत्रों का कहना है कि अरोड़ा ने अकाल तखत के जत्थेदार जसबीर सिंह रोडे के एक प्रमुख बयान को गलत ढंग से पेश किया, इसीलिए उन्हें निशाना बनाया गया. रोडे की ताजपोशी के तीन दिन बाद अरोड़ा ने लिखा था कि अकाल तख्त के जत्थेदार ने सिख पंथ का लक्ष्य 'खालिस्तान' मुकर्रर किया है. खुद रोडे के खंडन जारी करने पर यूएनआई ने उसी दिन यह खबर वापस ले ली थी. पुलिस सूत्रों के अनुसार अरोड़ा ने एक और गलत काम किया था. उन्होंने उग्रवादी नेताओं से प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) की इस खबर का खंडन करवाया कि स्वर्ण मंदिर में आधुनिक हथियार जमा किए जा रहे हैं और आतंकवादियों ने मंदिर परिसर में बंकर खोद लिए हैं. पुलिस का यह भी आरोप है कि अरोड़ा ने पंथक कमेटी के एक प्रवक्ता जागीर सिंह से उग्रवादियों के लक्ष्य का प्रचार करने में व्यावसायिक और निजी तौर पर सहायता देने का वायदा किया था.

अरोड़ाः रासुका में बंद

सभी फोटोः रवि भजारी

बलबीर सिंह सग्गू

के.एल. कमलेश

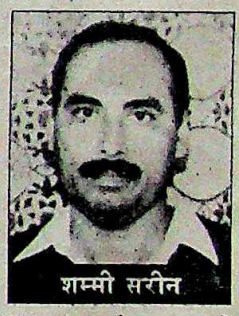

शम्मी सरीन

नरेंद्रपाल सिंह

मगर इनमें से कोई भी आरोप अधिकृत रूप से नहीं लगाया गया है. अमृतसर के पुलिस प्रमुख इज़हार आलम (जिनका अब जालंधर तबादला कर दिया गया है) के संक्षिप्त बयान के अनुसार अरोड़ा को राष्ट्रपति के आदेश से गिरफ्तार किया गया.

पत्रकारों का मानना है कि यदि अरोड़ा के खिलाफ आरोप सही हैं तो भी सरकार की कार्रवाई कड़ी है. अमृतसर में 'ट्रिब्यून' के प्रमुख संवाददाता पी.सी.एस. गिल कहते हैं, "यह गिरफ्तारी हम सभी को एक तरह से चेतावनी है कि हमें किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता है."

ये खाली धमकियां नहीं हैं. पिछले सात साल में उग्रवादियों ने सात पत्रकारों की हत्या और दर्जन भर पर हमले किए हैं. अभी पिछले साल पत्रकार नरेंद्रपाल सिंह पाल की भी हत्या कर दी गई. दूसरे पत्रकारों पर भी हमले हुए हैं. हिंद समाचार समूह के के.एल. कमलेश उग्रवादियों के हमले के बाद अभी भी नौ महीने से अस्पताल में हैं.

जो पत्रकार खबरों में धार्मिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश करते हैं, उन्हें तो सभी ओर से खतरों का सामना है. आतंकवादियों की तरह पुलिस के भी तत्काल सजा देने के अपने तरीके हैं. दो साल पहले 'नवां जमाना' के संवाददाता और छायाकार बलबीर सिंह सग्गू खबर जुटाने निकले थे कि पुलिस ने उनसे धक्का-मुक्की की. विडंबना है कि कुछ साल पहले उग्रवादियों ने स्वर्ण मंदिर के नजदीक सग्गू का स्टुडियो बंद करा दिया था. वह अभी तक नहीं खुल पाया है. 1984 के अंत में बीएसएफ और सीआरपी के जवानों ने पीटीआई और 'ट्रिब्यून' के दो संवाददाताओं के साथ मंदिर के निकट बदतमीजी की.

पंजाब में पत्रकारों को खतरा उन्हें धमकी भरे पत्र लिखने वाले आतंकवादियों से ही नहीं, सरकारी दमन और गिरफ्तारी से भी है

1984 में पुलिस ने 'ट्रिब्यून' के दलबीर सिंह के लिए जब गिरफ्तारी का वारंट जारी किया तो वे भूमिगत हो गए. पुलिस ने उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया. एक बार नहीं, दो बार. अभी पिछले ही पखवाड़े स्वतंत्र पत्रकार और मानव अधिकार कार्यकर्ता सुखदेव सिंह को 59वें संविधान संशोधन के विरोध में प्रदर्शन की अगुआई करते हुए चंडीगढ़ में गिरफ्तार किया गया.

राज्य के प्रेक्षकों का मानना है कि मौजूदा घटनाएं दरअसल केंद्र द्वारा राज्य में इमरजेंसी लगाने की रिहर्सल मात्र हैं. गिल कहते हैं, "हम तलवार की धार पर हैं." पंजाब में क्या हो रहा है यह जानने का अधिकार ही दांव पर लग गया है.

—बिपुल मुद्गल

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पवनशक्ति की महिमा न्यारी

अगर आज शेखचिल्ली होता तो देश के पहले पवन ऊर्जा मेगा-पार्क में बन रही बिजली उत्पादक पवनचक्कियां देखते ही उसकी आंखें चमकने लगतीं और उसका नेज़ा लहराने लगता. पवनचक्कियां शुरू करने का मौका पाकर तो वह आनंदातिरेक में उछल ही पड़ता. तमिलनाडु ऊर्जा विकास एजेंसी (टीएनईडीए) इस पार्क का निर्माण चिदंबरानार जिले में कयातर के पास कर रही है. इस अनोखे पार्क पर कुल लागत आएगी 15 करोड़ रुपए.

मदुरै-तिरुनेलवेली राजमार्ग पर पार्क में ये पवनचक्कियां लगाई गई हैं. हर एक में तीन पख हैं और प्रत्येक में 55 किलोवाट बिजली पैदा करने की क्षमता है. 7 अप्रैल को पार्क के पहले चरण की शुरुआत होते ही 22 मीटर ऊंची ये पवनचक्कियां काम करने लग गई हैं. टीएनईडीए को उम्मीद है कि वह सितंबर तक परियोजना के दूसरे चरण में 6 और पवनचक्कियां लगा लेगी जिनमें हरेक की बिजली उत्पादन क्षमता 200 किलोवाट होगी. और 1989 के अंत तक परियोजना के तीसरे चरण में मेगापार्क की कुल बिजली उत्पादन क्षमता 8.5 मेगावाट हो जाएगी.

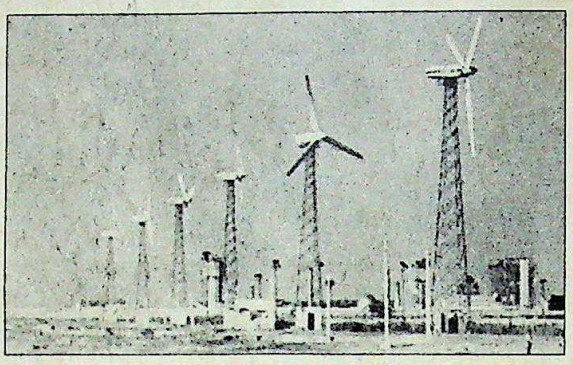

पार्क की पवनचक्कियां: अच्छा विकल्प

पिछले दो साल में गुजरात, महाराष्ट्र, ओडीसा और तमिलनाडु में बने 500-500 किलोवाट क्षमता के चार प्रायोगिक 'विंड फार्म' कामयाबी से चल रहे हैं. इन्हीं के मद्देनजर राज्य सरकार ने हवा का रुख पहचान लिया. टीएनईडीए के प्रबंध निदेशक एफ.जे. वाज कहते हैं, "पार्क के राजमार्ग पर होने से बहुतों को यह पता लगेगा कि पवनशक्ति ऊर्जा का एक विश्वसनीय और व्यावहारिक वैकल्पिक स्रोत है." हालांकि अनुमान यही है कि देश में पवनशक्ति से 5000 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है, पर अभी पवनचक्कियों के बड़े पैमाने पर निर्माण में बाधा है उनकी लागत जो ऊर्जा के दूसरे स्रोतों के मुकाबले निश्चय ही बहुत ज्यादा बैठती है.

निशाचरों को देखें दिन में

जो लोग निशाचर जानवरों के बारे में कुछ नहीं जानते, हैदराबाद का नेहरू चिड़ियाघर उनकी जानकारी बढ़ाने का इंतजाम कर रहा है. करीब एक साल पहले ही खोले गए चिड़ियाघर के निशाचर प्राणी विभाग में देश भर से जानवर लाकर रखे गए हैं. इनका सोने का सिलसिला जबरन बदल दिया गया है ताकि दर्शक चिड़ियाघर आएं तो जानवर जाग रहे हों.

हालांकि उनकी बाकी आदतों पर कोई असर नहीं पड़ा है. देश के इस पहले निशाचर पशु गृह में अब प्रजनन भी शुरू हो गया है. पूर्वोत्तर के राज्यों में यदा-कदा पाए जाने वाले शर्मीले बंदर (लोरिस) की मादा ने यहां के ही एक पिंजरे में पहले बच्चे को जन्म दिया है. फल-पत्तियां, कीड़े और कभी-कभार छोटे पक्षी तक खा जाने वाले इस जानवर के बारे में लोगों को कम ही जानकारी है

नगेंद्र राव

शर्मीले बंदर: लुप्तप्राय जीव

हैदराबाद के चिड़ियाघर की इन कोशिशों ने दिल्ली, लखनऊ और भुवनेश्वर के चिड़ियाघर प्रबंधकों को भी उत्साहित किया. वे भी अब निशाचर पशु गृह खोलने में दिलचस्पी ले रहे हैं. पर इन जानवरों को दर्शकों को दिखाना बहुत महंगा पड़ सकता है. इनकी मृत्यु दर भी काफी ज्यादा है, हालांकि अभी तक यह तथ्य जाहिर नहीं किया गया है.

पानी बना जाल

पानी का भी मछली पकड़ने के लिए चारे की जगह इस्तेमाल हो सकता है. आश्चर्य किंतु सत्य और संभव भी! लक्षद्वीप के मछुआरे 'ट्रूना' मछलियों को पकड़ने के लिए पानी ही इस्तेमाल करते हैं ताकि जिंदा चारे की जरूरत को कम किया जा सके.

इसके लिए जो तरीका अपनाया जाता है उसे यहां के बाशिंदे चमिंग कहते हैं. इसमें समुद्र की सतह पर समुद्री पानी की बौछार की जाती है. इससे 'ट्रूना' मछलियां समझती हैं कि छोटी मछलियां तैर रही हैं और वे शिकार के लिए सतह पर आ जाती हैं.

हर नाव पर दो लोग 'चमिंग' में लगे रहते हैं जबकि दूसरे परंपरागत बंसी से मछलियां पकड़ते हैं. कांटा ज्यादा नुकीला नहीं होता जिससे मछली घायल नहीं हो पाती. अब इस देसी तरीके में महत्वपूर्ण बदलाव आने जा रहा है. केंद्रीय मत्स्य तकनीक संस्थान, कोचीन के दो वैज्ञानिकों— पी.ए. पणिक्कर और श्रीधरन नंबूदिरी ने पानी की बौछार करने के लिए एक यंत्र तैयार किया है. लक्षद्वीप के मछुआरों के लिए संस्थान की इस भेंट से 'ट्रूना' मछलियों को पकड़ना अब काफी आसान हो जाएगा.

रहस्य बेधते गुब्बारे

गुब्बारे सिर्फ बच्चों का खेल ही नहीं हैं. वैज्ञानिक शोध में इनकी अहम भूमिका है और यह बात तभी स्पष्ट हो गई थी जब अक्तूबर 1956 में टाटा ऑयल मिल, सेवरी, बंबई से देश के पहले गुब्बारे ने उड़ान भरी थी.

यह बात पिछले महीने फिर पुख्ता हुई जब 11 अप्रैल को हैदराबाद की नेशनल बैलून फैसिलिटी (एनबीएफ) के 365वें गुब्बारे ने उड़ान भरी. 100,000 घनमीटर का यह गुब्बारा 36 किलोमीटर ऊंचाई तक गया और इस पर 250 किलोग्राम का एक यंत्र लदा हुआ था. इसके बाद वायुमंडल के अध्ययन के लिए यह लगातार दो-दो किलोमीटर नीचे आता गया.

इस तरह के वैज्ञानिक गुब्बारों से मौसम विज्ञान, समतापमंडलीय भौतिकी, अंतरिक्षी किरण भौतिकी और खगोलशास्त्र जैसे गूढ़ क्षेत्रों के आगे के अध्ययन में मदद मिली है.

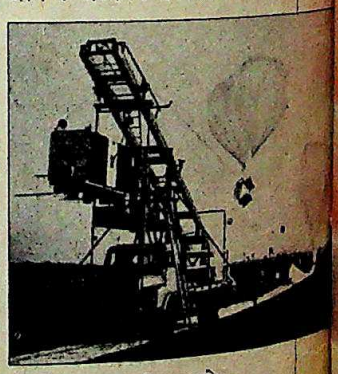

ऊपर जाते गुब्बारे

पर गुब्बारे बनाने वालों के सामने फिलहाल ज्यादा आधारभूत चुनौती है ऐसी फिल्म बनाने की जो जल्दी फूटे नहीं. एनबीएफ के मुखिया आर.टी. रेडकर के मुताबिक, "वैज्ञानिक गुब्बारों के लिए हम जल्द ही देश में कम घनत्व की लाइनर पालीएथलीन फिल्म बना लेंगे." भारतीय पेट्रोकेमिकल्स निगम लिमिटेड, वडोदरा ने फिल्म का एक नमूना तैयार किया है और एनबीएफ मई में इस देसी फिल्म की क्षमता परखेगा.

—अमरनाथ के. मेनन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारत महोत्सव

उगते सूरज के देश में सांस्कृतिक चकाचौंध

जापान के लोग इसे साकुरा कहते हैं—चेरी खिलने के इस मौसम में जापान की सुंदरता निखर उठती है. जापान में बहार जब अपने पूरे यौवन पर होती है, ऐसे ही वक्त भारत महोत्सव का रंगारंग नजारा जापानियों के रूबरू हुआ है. पर 15 अप्रैल को समारोह की शुरुआत से ठीक तीन दिन पहले ही आसमान में भूरे बादल घिर आए और तोक्यो में तो बाकायदा बर्फ गिरने लगी. महोत्सव की तैयारी में जुटे लोगों को शायद यह बुरा शकुन लगा हो. वैसे भी महोत्सव को लेकर जापानी बहुत उत्साहित नहीं थे.

हनेडा हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री राजीव गांधी की अगवानी के लिए भी कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं पहुंचा. और अगले दिन सुबह 'योमीयुरी' अखबार में राजीव को एलिजाबेथ टेलर से कहीं कम जगह मिली जो 'एड्स' नियंत्रण के अपने एक प्रकल्प के सिलसिले में प्रधानमंत्री नोबोरू ताकेशिता से मिलने आई हुई थीं.

लेकिन मौसम चमत्कारी ढंग से बदल गया और इसी के साथ जापानियों का मूड भी. महोत्सव का पहला हफ्ता जिस तरह नफासत से गुजरा उससे जापानियों को ही नहीं बल्कि भारतीयों को भी बेहद हैरत हुई.

उद्घाटन वैसे ही हुआ जैसे कि उद्घाटन हुआ करते हैं. दोनों प्रधानमंत्रियों ने दीप जलाए. फिर ताकेशिता एक ही सुर-लय में अपना भाषण पढ़ते गए. पर आखिर में हिंदी में 'भारत जापान मित्रता अमर रहे' कहकर उन्होंने सबको चौंका दिया. उद्घाटन के बाद राजीव सुरक्षा कर्मचारियों के घेरे में बालकनी में चले गए और वहीं से समारोह का आनंद लेते रहे.

डागर बंधुओं ने शिव स्तुति के ध्रुपद से कार्यक्रम शुरू किया. पर उनकी स्वर यात्रा अधूरी ही रही क्योंकि जापानी सीकों घड़ी के सिर्फ 13 मिनट ही उनके हिस्से में आए थे. सांस्कृतिक टीकाकार शांता सरबजीत सिंह का कहना था, "यह तो अमावस्या की रात में

संस्कृति तो स्पर्श मात्र से ही बदलाव कर देती है. यह एक दूसरे के अंतःस्थल तक पहुंचने का अवसर है

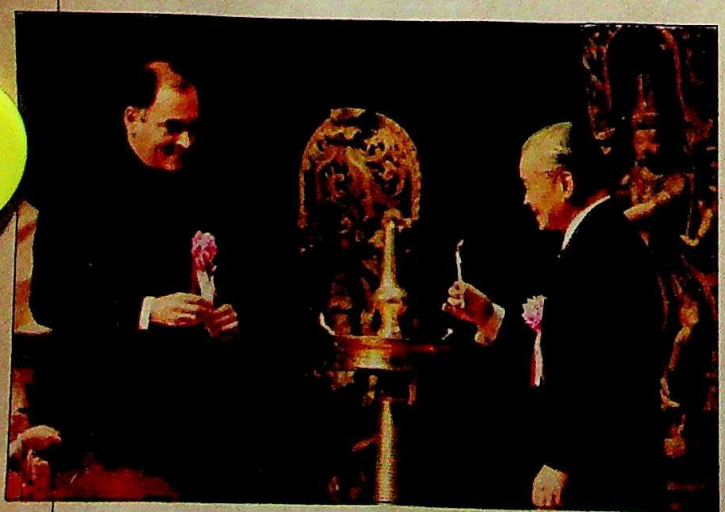

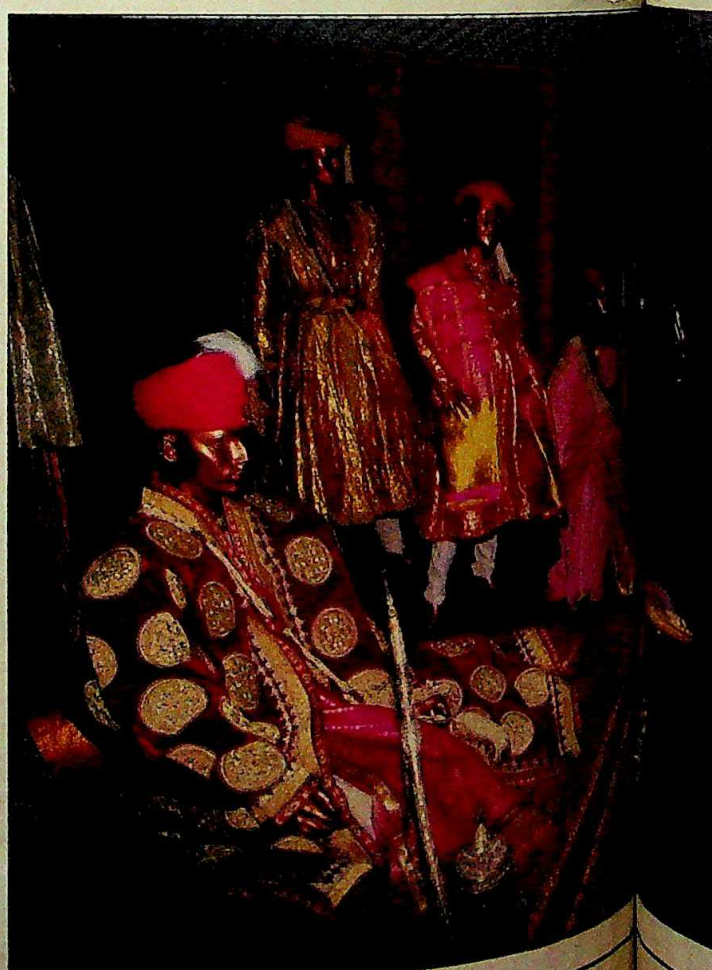

महोत्सव का उद्घाटन करते राजीव और ताकेशिता

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मोमबत्ती जलाने की तरह ही हुआ." पर शायद जापानियों ने इसे काफी पसंद किया. गुरु केलुचरण महापात्र का ओडिसी नृत्य और हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन बेहतर रहा. महोत्सव की अध्यक्ष पुपुल जयकर ने कहा, "संस्कृति स्पर्श मात्र से बदलाव कर देती है. यह पास आने का, एक-दूसरे के अंतःस्थल तक पहुंचने का अवसर है." जापानियों ने गरदन झुकाई और ऐसे दिखाया मानो उन्होंने यह बात समझ ली हो.

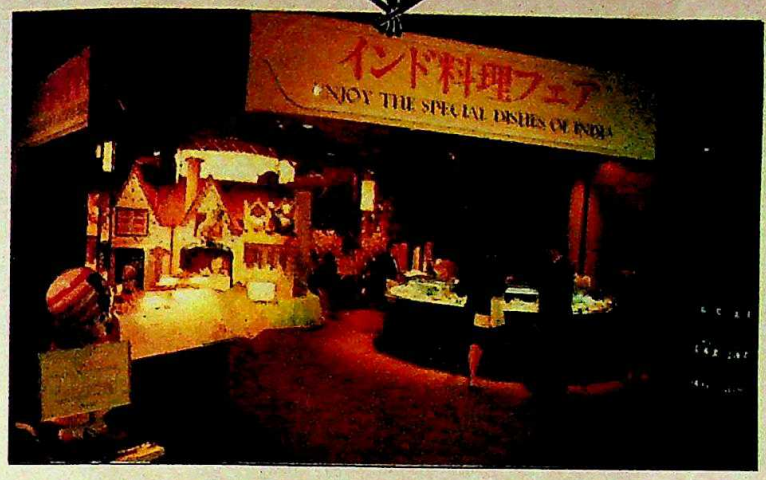

जापान में तमाम भारतीय समारोहों के प्रायोजक यहां के बड़े व्यावसायिक संस्थान हैं. इनमें बाजार में अच्छी साख वाला 'सेइबु' डिपार्टमेंटल स्टोर, जापान में सबसे ज्यादा प्रसार संख्या वाला 'योमीउरी' अखबार, और निप्पोन सांस्कृतिक केंद्र जैसे कितने ही नाम हैं.

अगले दिन जब मार्तंड सिंह ने भारत के शाही लिबासों का प्रदर्शन किया तो सब चकित रह गए. तोक्यो ने इससे पहले ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा था और अपने एक गरीब पड़ोसी एशियाई देश से उन्हें इसकी उम्मीद भी नहीं थी. सम्राट हिरोहितो के दूसरे बेटे अकीहितो को तो जैसे अपनी आंखों पर विश्वास ही न हुआ होगा. सोने की कढ़ाई का काला लहंगा पहने और चमचमाती हुई ओढ़नी ओढ़े स्त्रियों को देखकर राजकुमार ने मजाक किया, "मेरी बीवी को यहां ज्यादा देर मत रोकिए वरना वह इनमें से कुछ कपड़े हासिल करने के लिए बेताब हो उठेगी."

भारतीय व्यंजनों का स्टालः एक और आकर्षण

शाही ठाटबाट के प्रदर्शन के लिए कुल 10 लाख रु. का बजट था जबकि भारत के वनवासियों के लिए 20 लाख रु. रखे गए थे. स्टीमरों और गगनचुंबी इमारतों के तटवर्ती शहर कोबे में बनवासी शिल्प का प्रदर्शन हुआ जिसमें भारतीय शिल्प की तीन बड़ी हस्तियों—दिल्ली शिल्प संग्रहालय के ज्योतींद्र जैन, भारत भवन के स्वामीनाथन और हकू शाह का सहयोग था. तकरीबन 500 वनवासी इलाकों से इकट्ठा किए गए ये चुनिंदा नमूने नए नहीं थे. पर एक साथ रखे गए इन

शाही परिधानों की प्रदर्शनीः प्राचीन शान

संजय आचार्य

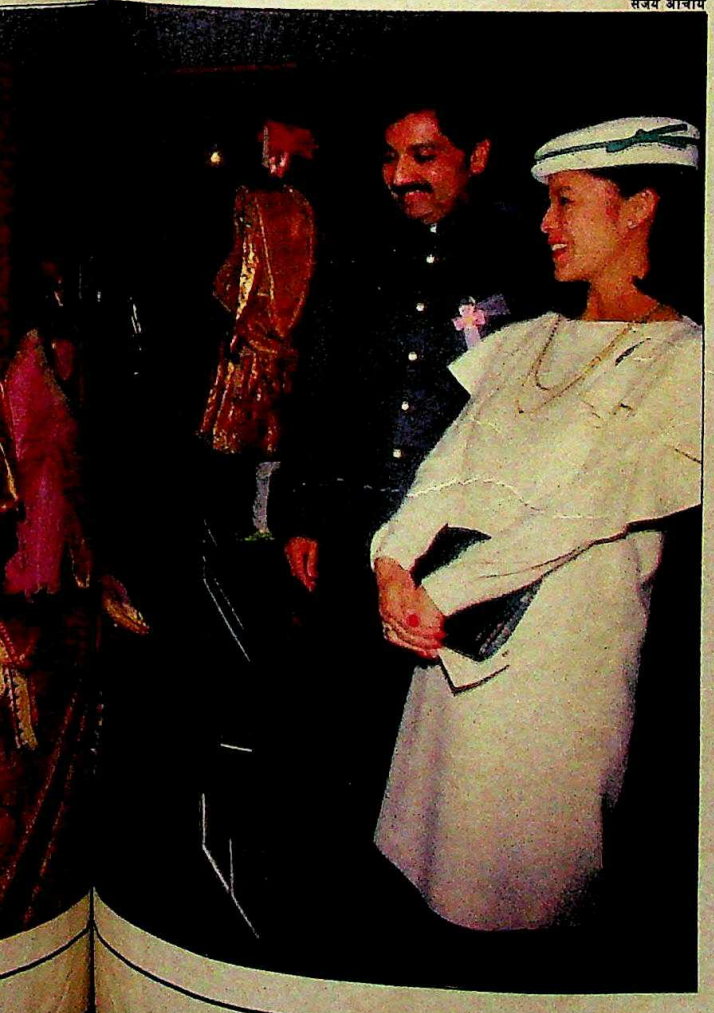

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दोनों नेताः सदभाव का समां

नमूनों में ग्रामीण जीवन की सोंधी महक थी.

पूरे आयोजन में कहीं कोई खामी नहीं थी. सब कुछ तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक ही हुआ वरना पहले बहुत से प्रदर्शनों में यह सब हुआ है. 32 शहरों में होने वाला यह महोत्सव क्या सचमुच बिना किसी बाधा के संपन्न हो सकेगा? जयकर के मुताबिक यह "किसी भी महोत्सव का सबसे कम" बजट था. तोक्यो के भारतीय दूतावास का दावा है कि समारोह के वास्ते विदेशी मुद्रा में एक भी पाई नहीं खर्च की गई.

समय आ गया है कि दुनिया भर में अपनी सांस्कृतिक ताकत के प्रदर्शन के बाद अब भारत को इसका फायदा भी मिले

उधर अधिकारी भी ऐसी ही कामयाबी की उम्मीद में हैं कि शायद महोत्सव ही सांस्कृतिक संबंध प्रगाढ़ करने में सफल हो जाए. गुरमीत बावा, जफर हुसैन जैसों की लोक कलाकारों की टोलियां जापानी द्वीपों के दौरे पर हैं और इनके कार्यक्रमों की टिकटें पहले ही बिक गई हैं. मई में प्रदर्शित होने वाले पीटर ब्रुक के 'महाभारत' की 30,000 येन (3,000 रु.) से लेकर 60,000 येन (6,000 रु.) तक की सारी टिकटें बिक चुकी हैं. जापान में भारतीय राजदूत ए. महादेवन कहते हैं, "महोत्सव के आखिर में वे सोचने पर मजबूर होंगे. यहां पहल हमें करनी होगी और इसके लिए संस्कृति सबसे बढ़िया माध्यम है. हम राजनीति और आर्थिक मुद्दों पर बातचीत एक साथ आगे बढ़ाएंगे."

अब जबकि भारत दुनिया भर में अपनी सांस्कृतिक ताकत का प्रदर्शन कर रहा है तो इसका लाभ भी उसे मिलना शुरू होना चाहिए. पुपुल जयकर कहती हैं, "आप देखिएगा, जापानी पर्यटकों की संख्या में भारी बढ़ोतरी होने वाली है. समस्या हमारे पास पर्याप्त मात्रा में होटल न होने की है." 'सेइबु' के उत्पाद महाप्रबंधक अकीरा मोचीजुकी भविष्यवाणी करते हैं, "भारतीय वस्त्रों और फैशन के दूसरे साजो-सामान की अगले साल जापान में भारी मांग होगी." इस मांग को पूरा करने की तैयारी में मोचीजुकी खरीदारी करने सितंबर में भारत आ रहे हैं. जापान में भारत महोत्सव भले ही इस साल हो रहा है पर हर किसी का अनुमान है कि भारत का महत्वपूर्ण साल तो महोत्सव खत्म होने के बाद ही शुरू होगा.

फलदायक रिश्तों के संकेत अभी से मिलने लगे हैं. फैशनेबल वस्त्रों के मामले में जापानी बाजार वस्तुतः अभी अछूता ही है और यहां समृद्धि भी काफी है. यहां के अमीर तो बहुत ज्यादा अमीर हैं ही, गरीबों के पास भी काफी पैसा है. चार साल पहले बंबई के नौजवान जौहरी अतुल पारिख ने जापान के एक प्रमुख आभूषण डिजाइनर काजुओ ओगावा के साथ कारोबार शुरू किया. इनका कारोबार 40 लाख येन तक पहुंच चुका है. अब ये लोग जापान की नौजवान महिलाओं के लिए मीना के तरह-तरह के गहने बनाने में लगे हैं जिनमें भारतीय मंदिरों और खंडहरों की नक्काशी के आधार पर जड़ाऊ पिनें बनाना भी शामिल हैं. इन पिनों पर मंदिर के कलश से लटकता कृष्ण झूला (कीमत 60 लाख येन), हंस की शक्ल का बजरा (30 लाख येन), मिकी-मोटो हीरों से जड़े खंजर और मोर आदि की नक्काशी होगी.

हनेई मोरी की तड़कभड़क वाली फैशन प्रदर्शनी से भी फैशन की बिक्री की संभावनाएं दिखती हैं. इक्कट वाली कढ़ाई के वस्त्रों, कश्मीरी तर्ज पर बुने गए शुद्ध रेशम के कपड़ों और भारत में दुलहन के पहनावे जैसे पूरी तरह भारतीय वस्त्रों को ही तोक्यो के बेहद फैशनेबल डिजाइनों का रूप दिया है.

महोत्सव का कम उजागर पर शायद बेहद महत्वपूर्ण पक्ष भारत और भारतीय वस्तुओं के बारे में बनाए गए सुव्यवस्थित विवरण पत्र रहे. प्रत्येक प्रदर्शनी के लिए प्रायोजकों ने विस्तृत जांच-परख और सुंदर तस्वीरों के साथ विवरण पुस्तिकाएं तैयार करवाई हैं. फिल्में भी बनाई, चित्रों को नया रूप दिया और सभी विषयों की विस्तृत जानकारी इकट्ठी की. 2000 साल की भारतीय सभ्यता से जो कुछ हम हासिल नहीं कर पाए, जापानी अगले कुछ महीनों में ही शायद हासिल कर लेंगे. यहां तक कि 'सेइबु' में एल्यूमिनियम की बाल्टियों, साइकिल रिक्शाओं, वीडियो पर महमूद के हंसी-मजाक और इत्र की महक से भरापूरा चांदनी चौक जैसा बाजार बनाने के लिए भी जापानियों ने करीब डेढ़ साल शोध किया. यदि वे हमारे इतिहास को सुव्यवस्थित विवरण पुस्तिकाओं के रूप में बनाकर हमें लौटाते हैं तो हमारे लिए यह एक धरोहर बन जाएगी.

इस बीच महोत्सव पूरे जापान में छा गया है. जापान के सभी द्वीपों में जल रहे भारतीय दीप मानो बता रहे हैं कि बुद्ध के देश में कितनी सांस्कृतिक अनेकता है और वह उनके येन खर्चने के लिए कितना उपयुक्त स्थान है. यह दक्षिण एशिया में भारत का पहला प्रमुख सांस्कृतिक अभियान है. इसमें भारत के निरंतर बदलाव को प्रदर्शित करती फिल्में, समकालीन कला प्रदर्शनियां और टैगोर पर एक प्रदर्शनी दिखाई जाएंगी. उधर नारा में गुरु केलुचरण और चौरसिया एक बड़े कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. अगले छह महीने तक भारत की मौजूदगी का एहसास हर कहीं होगा. दोनों देशों के बीच फायदेमंद करार होंगे, सो अलग.

विदेशों में भारत महोत्सवों की धूमधाम के बीच इन्हें न देख पाने वाले भारतीयों के मुंह से शायद यही निकले, "काश, ऐसा महोत्सव भारत में भी होता."

—सिमरन भार्गव, तोक्यो और कोबे में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"आँखें बन्द रहने पर भी मैं बता सकती हूँ फ़र्क..."

नया

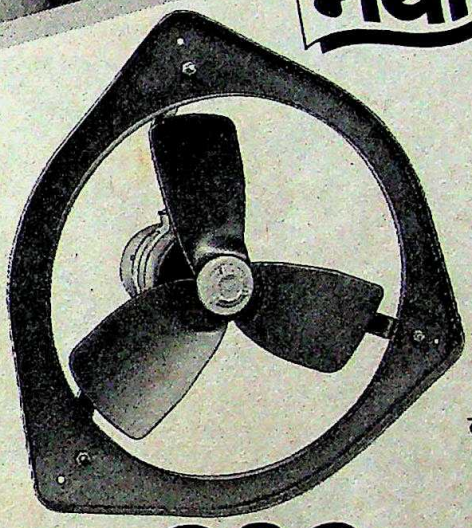

GEC Ventilair फ़ैन

चन्द मिनट में पायेंगे कमरे में ताज़गी का एहसास

वेन्टिलेअर पलक मारते ही बाहर फेंक देता है भाप, धुआँ और बदबू । जीईसी की अन्तर्राष्ट्रीय टेक्नॉलाजी की मदद से लैस, वेन्टिलेअर आज के अग्रणी ब्रांडों के मुकाबले २५% ज़्यादा कार्यक्षम है ।

इसकी खामोश उपस्थिति का आनंद लूटिए

वेन्टिलेअर खामोशी से काम करता है । इसका आधुनिक एअरो डायनॅमिक डिज़ाइन कम से कम आवाज़ के साथ ऊँचे दर्ज़े के काम की पूरी गारंटी है । खास किस्म के कम्पन-रोधक माउन्टिंग पैड और डबल बॉल बेयरिंग इसे बनाते हैं बिल्कुल बेआवाज़ ।

इसकी तकनीकी उत्तमता का अनुभव खुद कीजिए

साँचे में ढली अल्युमिनियम बॉडी, स्टील ब्लेड और बेदाग़ कारीगरी की वजह से, वेन्टिलेअर है आज तकनीकी दृष्टि से अपने ढंग का सर्वाधिक उन्नत फ़ैन । इसका अनोखा डिज़ाइन बिना मरम्मत जीवनभर चलने की है पूरी गारंटी ।

आंख मूंद कर खरीद लीजिए वेन्टिलेअर

जीईसी की विश्वव्यापी टेक्नॉलॉजी पर भरोसा कीजिए, हमेशा सर्वोत्तम सामान लीजिए

आज ही एक वेन्टिलेअर घर लाइए

GEC
GEC
GEC

घर लाइए जी ई सी की अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञता

Trade Mark GEC Permitted user : The General Electric Company of India Limited

TSA-C. GEC. V I

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

राजीव की यात्रा

सुहाने सफर की सफलता

प्रधानमंत्री की टोली का आधा वक्त आसमान में गुजरा

तोक्यो के विशालकाय 'न्यू ओटानी होटल' के कर्मचारियों के लिए उसकी 38वीं मंजिल के कमरों में ठहरे पति-पत्नी कोई खास महत्व नहीं रखते थे. वे वीआईपी अतिथियों की कंप्यूटर की लंबी फेहरिस्त में मात्र श्री और श्रीमती आर. गांधी ही थे. यह सुनकर कि दरअसल ये अतिथि भारत के प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी हैं, होटल के प्रमुख खजांची की आंखें फैल गईं. उसने अविश्वास से पूछा, "आपके प्रधानमंत्री इस होटल में ठहरे हैं? वे सरकारी अतिथि-गृह में क्यों नहीं ठहरे?"

यदि आप जापानी हैं तो आपके लिए यह एक जायज सवाल है. लेकिन यदि आप देश के तेजी से फलते-फूलते निर्यात घराने—भारत महोत्सव 'कार्पोरेशन'—की जापानी शाखा के उद्घाटन के लिए वहां एक दिन के लिए गए राजीव गांधी की यात्रा टोली में हैं, तो इस सवाल से परेशान हो सकते हैं.

राजीव की यह न तो सरकारी यात्रा थी न ही राजकीय दौरा और न ही कोई व्यक्तिगत या गैर-सरकारी यात्रा ही.

इसका फल यह हुआ कि तोक्यो के अखबारों ने राजीव के आगमन के बारे में अपने भीतरी पन्नों पर सिर्फ एक पैरे की खबर लगाई. हनेडा हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी के लिए जापानी सरकार का मुख्य प्रोटोकोल अधिकारी ही पहुंचा था. प्रधानमंत्री के राजकीय दौरे में आम तौर पर सरकारी प्रीतिभोज और प्रवासी भारतीयों के साथ बैठक का कार्यक्रम शामिल रहता है पर यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ.

लेकिन इनकी भरपाई के लिए राजीव के पास अपने विमान 'हर्षवर्द्धन' में पर्याप्त व्यवस्थाएं थीं. एअर इंडिया के इस 747 विमान में ही बेल-बूटेदार दस्तरखान पर सजे चांदी के बर्तनों में शानदार पांच सितारा खाने की व्यवस्था थी. तरह-तरह की शराब और शैंपेन थी सो अलग (राजीव ने फलों का ताजा रस ही लिया).

और इन दिनों राजीव की पत्रकारों से बातचीत कभी-कभार ही हो पाती है इसलिए जब वे अपने भव्य सूट से निकलकर विमान के मध्यभाग में 20 सदस्यीय पत्रकार दल से मिलने दो बार आए तब ऐसा लग रहा था मानो यह बैठक जापान में स्थित भारतीय समुदाय के साथ ही हो रही है. लेकिन इन बैठकों से यही जाहिर हुआ कि समस्याओं से घिरे होने के बावजूद राजीव में अभी भी बैठक को दिलचस्प बनाने की क्षमता है. उनकी बातचीत, हंसी-मजाक से लग रहा था जैसे वे वही पुराने राजीव हों 1984 वाले.

इस बैठक में उनकी हाजिर-जवाबी की भी झलक मिली. वे सवालों का जवाब छूटते ही दे रहे थे. मसलन 'सिख उग्रवादियों का आरोप है कि पंजाब में हाल की कुछ हत्याएं सरकारी एजेंटों ने की हैं' जैसे उलझे सवाल का जवाब भी उन्होंने छूटते ही दिया, "मैं आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहूंगा कि पाकिस्तान में उग्रवादियों के प्रशिक्षण के लिए बने कैंपों से हमारा कुछ लेना-देना नहीं है." पर इस हल्के-फुल्के वातावरण के बावजूद उनके इर्द-गिर्द का सुरक्षा घेरा एक मिनट के लिए भी ढीला नहीं पड़ा.

इस यात्रा से यह भी जाहिर हुआ कि प्रधानमंत्री के अपने करीबी सहायकों के साथ मधुर संबंध हैं. पत्रकार वार्ता के दौरान वे मणिशंकर अय्यर को 'मणि', मोंटेक सिंह अहलूवालिया को 'मोंटेक' और दून स्कूल तथा कॉलेज के साथी सुमन दुबे को स्कूल का उनका उपनाम 'सुमी' कह कर बुलाते रहे.

सभी फोटो: प्रणव मुखर्जी

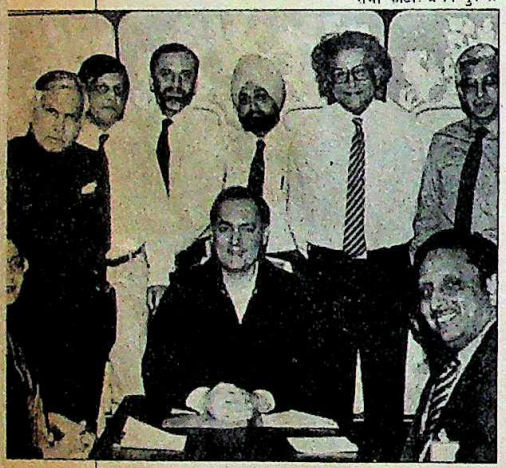

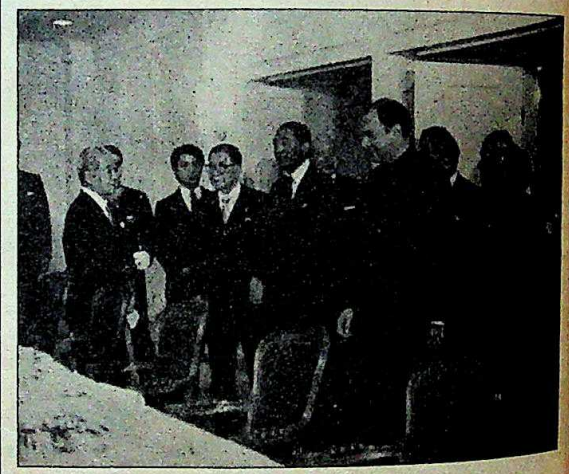

विदेशी आबोहवा में मानो ऐसा कुछ है जो राजीव गांधी को बदल देता है. अपने सहायकों के साथ अनौपचारिक संबंधों का इजहार हो या जापानी व्यापारियों का मन मोह लेने का अंदाज, लगा जैसे वे वही पुराने राजीव गांधी हों 1984 वाले

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लेकिन अपने बुजुर्ग तथा वरिष्ठ सहयोगियों के लिए वे ऐसी अनौपचारिकता नहीं बरत रहे थे. वे विदेश राज्यमंत्री नटवर सिंह को उनका पूरा नाम लेकर बुला रहे थे और योजना आयोग के सदस्य आबिद हुसैन को हमेशा 'आबिद हुसैन जी' ही कह रहे थे.

जापानी दौरे के पहले के कार्यक्रमों में हिरोशिमा का एक दिन का दौरा भी शामिल था. पर 747 विमान हिरोशिमा हवाई अड्डे पर नहीं उतर सकता था इसलिए राजीव की यात्रा टोली यह मौका चूक गई. एअर इंडिया के अधिकारियों का कहना था कि राजीव विशालकाय जंबो जहाज के बदले 737-बोइंग विमान का चयन कर सकते थे. लेकिन 400 लोगों के लिए उपयुक्त विमान में सिर्फ 80 लोगों को ले जाने का नतीजा यह हुआ विमान में बोझ कम हो गया और सामान्य तौर पर लगने वाले झटकों से कहीं ज्यादा झटके झेलने पड़ गए.

पर लौटते वक्त जंबो ने अपेक्षाकृत कम झटके खाए क्योंकि तोक्यो में खरीदे गए सामान ने बोझ बढ़ा दिया था. खरीदारी में बाजी मारी राजीव के व्यक्तिगत नौकर मदनलाल ने. मदनलाल तीन भारी-भरकम बैग लिए जहाज में आया. जब एक सुरक्षा कर्मचारी ने उसकी फिजूलखर्ची पर उसे छेड़ा तो मदनलाल का जवाब था, "एक में कंप्यूटर है." पर उसने यह नहीं बताया कि कंप्यूटर वह अपने मालिक के लिए ले जा रहा था या 1, रेसकोर्स रोड में भोजन की फेहरिस्त तैयार करने के लिए.

पर उसके उच्च-तकनीक प्रेमी मालिक को जापान की इस एक दिन की यात्रा में निश्चित ही खासी कामयाबी मिली. जापानी प्रधानमंत्री नोबोरू ताकेशिता से मुलाकात में उन्होंने भारत में जापानी पूंजी निवेश बढ़ाने का वायदा करवा लिया. लेकिन भारत में जापानी पूंजी निवेश कितना बढ़ेगा यह जापानी उद्योग के दिग्गजों के साथ राजीव की बातचीत के नतीजे ही बताएंगे.

उद्योगपतियों के साथ बैठक में हाजिर रहे अधिकारियों के मुताबिक वहां राजीव ने सामने वाले को लाजवाब कर देने की क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया. जब जापानी मेजबान ने उद्योगपतियों का परिचय दिया तब उन्होंने परंपरा के अनुसार झुककर उनका अभिवादन किया. जब राजीव की बारी आई तब उन्होंने भी अपने प्रतिनिधिमंडल का परिचय देकर उद्योगपतियों का झुककर अभिवादन किया. इस अंदाज से जापानी खुश हो गए खासकर इसलिए भी कि राजीव ने इसे बड़ी नफासत के साथ किया.

उन्होंने भारत की कारोबारी दुनिया की अड़चनों की भी खुलकर चर्चा की ("निहित स्वार्थ, संरक्षित बाजार और प्रक्रिया में लगने वाली देरी" के बारे में). उन्होंने यह भी वायदा किया कि प्रधानमंत्री सचिवालय की देखरेख में जापानी उद्योगपति विशेष प्राथमिकता पा सकेंगे जिससे भारतीय कंपनियों से उनके मेलजोल और लाइसेंस पाने में देरी नहीं हो पाएगी. भारतीय प्रतिनिधिमंडल के लिए यह संकेत था. और वित्त सचिव एस. वेंकटरमनन ने घोषणा कर डाली कि वे जापानी औद्योगिक प्रस्तावों को 'फौरन मंजूरी' दिलवाएंगे और कहा, "यह मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी. मैं जानता हूं कि मैं अपनी गरदन फंसा रहा हूं पर यह घोषणा मैं अपने प्रधानमंत्री के सामने कर रहा हूं." राजीव ने मुस्कराकर इसके प्रति अपनी मौन सहमति जाहिर की.

लेकिन सोनिया सार्वजनिक कार्यक्रमों में नहीं के बराबर दिखीं. वे सिर्फ भारत महोत्सव के उद्घाटन के अवसर पर हाजिर थीं. लेकिन इसमें भी वे पीछे बालकनी में बैठी हुई थीं और उनके पति ने अपने भाषण के अंत में शुद्ध उच्चारण करते हुए जापानी में 'अरीगातो गोजायमासू' (आप सबको धन्यवाद) कहकर लोगों का मन मोह लिया.

इस यात्रा के बाद विएतनाम में छह-घंटे का पड़ाव फीका लग रहा था. राजकीय दौरे पर आए प्रधानमंत्री को देखने के लिए लगता था पूरा हो ची मिन्ह शहर (पहले सैगोन) ही उमड़ पड़ा है. लेकिन लंबे युद्ध की विभीषिका झेल चुके विएतनाम में दूसरे देशों के पर्यटकों के आकर्षण लायक शायद ही कुछ बचा है. एकमात्र आकर्षण शायद यहां का भोजन ही है. सरकारी प्रीतिभोज में पांच तरह के व्यंजनों को देखकर प्रधानमंत्री के प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों में खुशी की लहर दौड़ गई. इन व्यंजनों में नारियल के खोल में परोसा गया नारियल और दूध का सूप, रसदार लोबस्टर, भूने हुए बत्तक और फलोंवाली आइसक्रीम थी. पर यहां जापान वाली बात नहीं थी. राजीव के एक सहायक ने चुटकी ली, "हम सैगोन को सैगोन ही रहने देना चाहते हैं."

—**दिलीप बॉब**, तोक्यो और हो ची मिन्ह सिटी में

दिलीप बॉब

एपी/पीटीआई

पूरी यात्रा में राजीव ही छाये रहे. सोनिया बस उनके पीछे-पीछे ही दिखीं. और खरीदारी में भी बाजी उनके नौकर मदनलाल ने मारी जिसने तोक्यो में तीन बैग भर कर खरीदारी की. लेकिन विएतनाम की यात्रा जापान जैसी दिलचस्प नहीं रही

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अफगानिस्तान

अमन का फैसला बंदूकों से

रूसी फौजें तो लौट जाएंगी पर कबीलाई संघर्ष नहीं टलेगा

*अफगानिस्तान मौजूदा दौर की बड़ी त्रासदियों में से एक है. एक ऐसी त्रासदी जो अपने समाज के भीतर रची-बसी कबीलाई हिंसा, बदला लेने के भाव से उपजी है, झगड़ालू पड़ोसी और महाशक्ति ने दखल देकर जिसे और भयावह बना डाला है. एक ऐसी त्रासदी, जो समझौते तक से और उलझ गई है. अब हर अफगान अपने दुश्मन अफगान से भिड़ने को तैयार बैठा है क्योंकि महाशक्तियों ने पिछले महीने जेनेवा में शांति समझौता करके उनके लिए मैदान खुला छोड़ दिया है. पिछले पखवाड़े काबुल का माहौल एक साथ ही खुशी और दहशत में डूब गया और आठ साल से भी ज्यादा समय तक काबुल में रहने के बाद रूसी फौजों ने बोरिया-बिस्तर समेटना शुरू कर दिया. जंग की जद्दोजहद में घिरे इस मुल्क में मौके पर मौजूद थे विशेष संवाददाता **शेखर गुप्ता** और मुख्य फोटोग्राफर **भवान सिंह**. उनकी रिपोर्ट.*

काबुल में युद्ध की विभीषिका में बची दुकानों में दंतकथाओं की एक छोटी-सी किताब है. उसमें एक छोटे-से गांव चिल्दुख्तारन का जिक्र मिलता है. इस गांव को 40 कुंआरी कन्याओं का घर भी कहा जाता है. शताब्दियों पहले लोग काबुल नदी के जुल्म से परेशान थे. एक बार राजघराने की 40 कुंआरी कन्याओं ने तय किया कि वे नदी पर बांध बनाएंगी. जैसे ही बांध बनाने का काम पूरा हुआ, आसपास की पहाड़ियों से नास्तिकों का एक हुजूम उतरा और उसने इन कन्याओं पर हमला बोल दिया. कन्याओं ने मदद के लिए फरिश्तों की इबादत की. बिजलियां कड़क उठीं और आंधी-तूफान शुरू हो गया जिसके झोंके में हमलावर नास्तिक उड़ गए और बांध भी. और जब आसमान साफ हुआ तो नदी के किनारे इन कुंआरी कन्याओं की लाशें बिछी पड़ी थीं.

काबुल के 20 किलोमीटर दक्षिण में, सामरिक महत्व के राजमार्ग लोगार (देखिए नक्शा) पर आज भी इन 40 कुंआरी कन्याओं का मकबरा मौजूद है. गांव चिल्दुख्तारन भी वहीं है. इसके प्राचीन खंडहर और मौजूदा बाशिंदे दोनों उस सर्वनाश के प्रतीक हैं जिसकी आशंका से पूरा अफगानिस्तान दहशत में डूबा हुआ है. लगता है, इस बार भी तबाही उस दंतकथा से कम नहीं होगी.

गांव के सयाने बुजुर्ग और मुखिया नसीरुल्ला तबाही का अंदेशा जाहिर करते हैं. वे कहते हैं, "मैंने सुना है कि कोई समझौता हुआ है और 'शौराबी' (रूसी) चले जाएंगे पर जंग खत्म नहीं होने वाली." उनकी आंखें उस समय चमक उठती हैं जब वे दूसरे विश्व-युद्ध के समय की अपनी पुरानी ली एनफील्ड 303 राइफल के बारे में बताते हैं.

लेकिन आज गांवों के नौजवान अपनी नई

एक सशस्त्र ग्रामीण रक्षक (नीचे) और किशोर योद्धाः मुकाबले के मूड में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अफगानिस्तान तो एक अलहदा मुल्क है. यहां हर बात का फैसला बंदूक से होता है. अमन लौटे या नहीं यह भी अब बंदूकों से ही तय होगा

और खतरनाक रूसी कैलाश्निकोव के दीवाने हैं. ये नौजवान इन रूसी बंदूकों को लाठी की तरह लिये घूमते हैं. उन्हें मरने-मारने की पूरी छूट मिली हुई है. ये सब नवगठित ग्रामीण सुरक्षा बल के सदस्य हैं. अब भी जो थोड़े बहुत ग्रामीण इलाके नजीबुल्लाह सरकार के नियंत्रण में बने हुए हैं उनकी हिफाजत के लिए सरकार ने यह ग्रामीण सुरक्षा बल बनाया है. चिल्दुख्तारन गांव जिस जिले में पड़ता है उस चरसियाब जिले में सत्तारूढ़ पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान (पीडीपीए) के महासचिव मुहम्मद मुजमिल का दावा है, "ये लोग शांति सैनिक हैं. अगर लड़ाई यहां तक आ पहुंची तो ये नियमित फौज की तरह ही असरदार साबित होंगे." लड़ाई चिल्दुख्तारन और इसके पड़ोसी गांवों तक पहुंच भी चुकी है.

ज्यादातर लोग मानते हैं कि रूसियों के जाने का मतलब होगा गुटों में बंटे अफगानों के लिए जंगे-मैदान को खुला छोड़ देना. एक राजनयिक के मुताबिक डेढ़ करोड़ लोगों के इस मुल्क में अमन की उम्मीद करना बेकार है क्योंकि यहां इतने स्वचालित हथियार हैं जितने भारत और पाकिस्तान की फौजों के पास कुल मिलाकर भी नहीं हैं.

काबुल में सरकार चला रहे वामपंथियों को भी इस मुद्दे पर कोई भ्रम नहीं है. नई दिल्ली में सात साल तक राजदूत रह चुके उप प्रधानमंत्री मुहम्मद हसन शर्क़ मानते हैं, "यह कहना गलत होगा कि इस देश के पूरे भू-भाग पर हमारा नियंत्रण है और सोवियत फौजें लौटने के बाद सब ठीक हो जाएगा."

काबुल की सरकार हकीकत से कितनी रूबरू है इसका पता इस बात से भी चलता है कि उसने 1983 में ग्रामीण विकास मंत्रालय खत्म कर दिया था. पर पिछले पखवाड़े इस मंत्रालय को फिर से कायम कर दिया गया.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नक्शा: बी.के. शर्मा

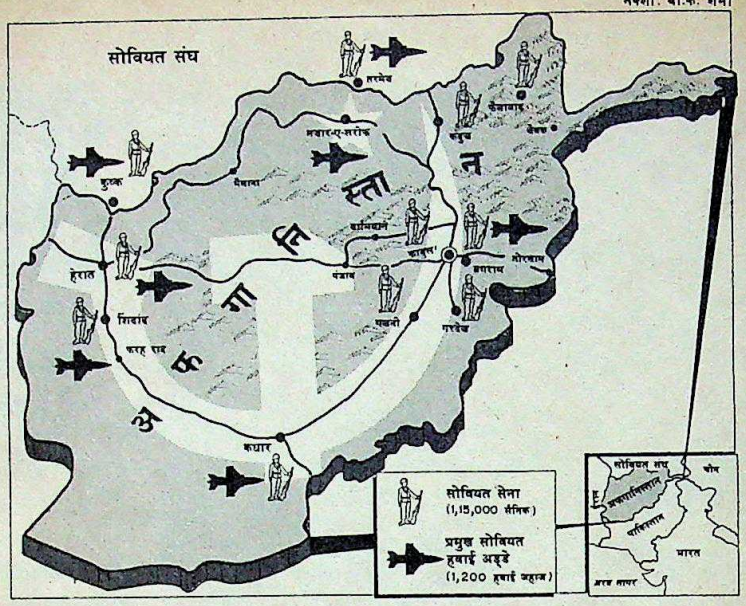

हालांकि पश्चिमी सूत्र मानते हैं कि काबुल की सरकार अब भी 15 फीसदी से ज्यादा ग्रामीण इलाकों पर अपना नियंत्रण कायम नहीं कर पाई है, पर सरकार खुद 50 फीसदी ग्रामीण इलाकों पर नियंत्रण का दावा करती है. फिर भी उसने सचाई को कबूल करते हुए राष्ट्रीय परिषद के 229 में से एक चौथाई चुनावी हलकों में चुनाव न कराने का फैसला किया. इन्हें 'विपक्ष' के लिए 'आरक्षित' छोड़ दिया गया. मुजाहिदीनों को सरकार 'विपक्ष' कहना ही पसंद करती है. सरकार की दलील यही है कि "हम उन सबसे जंग नहीं जीत सकते. हमें तो दुलार और फटकार की नीति पर ही चलना होगा." पर काबुल में इस नीति का चरम रूप देखा जा सकता है. मिसाल के लिए सरकार का बहुप्रचारित शांति प्रस्ताव बख्तरबंद गाड़ियों के बुर्जों पर से प्रचारित किया जा रहा है. काबुल की सड़कों पर ये फौलादी दैत्य दौड़ते रहते हैं. इनके बुर्जों पर बैठे सैनिक झुक-झुककर पर्चे बांटते हैं.

बहरहाल, काबुल के कूटनयिक हलकों में चर्चाओं के अनुसार सोवियत नेताओं को न तो ज्यादा फिक्र अफगानियों के नाशुक्रेपन की है और न वहां मारे गए अपने 16 हजार सैनिकों की. बल्कि वे अपनी सेनाओं के गिरे हुए मनोबल और उनकी अनुशासनहीनता के बारे में कहीं ज्यादा चिंतित हैं. नशेबाजी और

अमन के पर्चे बांटते सैनिक

'पश्चिमी ह्रास' के चिन्ह काबुल में जहां-तहां देखे जा सकते हैं. काबुल की कूचा-ए-मुर्गा सड़क पर दुकानों में सोवियत रसद की खुलेआम बिक्री होती है. उदाहरण के लिए कावियार का एक डिब्बा मात्र 60 अफगानी (6 भारतीय रु.) में और मैकरेल या टूना मछली का डिब्बा इससे भी कम में खरीदा जा सकता है. इसी तरह यूगोस्लावी फ्रैंकफर्टर, बुल्गारियाई आलूबुखारे का जैम और यहां तक कि प्रसिद्ध स्टालिचनाया वोदका की एक लिटर की बोतल भी मात्र 80 रुपए में खरीदी जा सकती है. थोड़ी-सी दोस्ती के बाद ही कोई अफगान दुकानदार चटखारे ले लेकर बता देगा कि किस तरह रूसी सैनिक अपने ट्रकों से उतरकर आते हैं और यह माल तथा पेट्रोल व डीजल बेच जाते हैं. इस सबके बदले में वे डॉलर लेते हैं जिनसे वे घर लौटते समय वीसीआर नहीं तो सोनी कंपनी के टू-इन-वन जैसी चीजें तो जरूर खरीदते हैं.

चौंकाने वाली बात यह है कि नजीब की

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

क्रांतिकारी सरकार के बावजूद अफगानी समाज पर पश्चिमी प्रभाव लगातार बढ़ता गया है. वहां 'मेहनतकश' मजदूर समाज के कई लोगों को अक्सर नाइक कंपनी के जूते और स्टेफोर्ड कंपनी की टाइयां पहने देखा जा सकता है. महिलाओं में भी द. कोरिया की नकली जुराबें और परफ्यूम काफी लोकप्रिय हैं. वहां के 'होटल काबुल' में लगभग हर शाम किसी शादी की दावत में जवान जोड़ों को हिंदी फिल्मों के 'आवारा हूं' से लेकर 'रंबा हो' जैसे गीतों की धुन पर नाचते हुए देखा जा सकता है. लेकिन इन पार्टियों में पहुंचने से पहले सड़क पर इन मेहमानों को सोवियत सैनिकों के हाथों तलाशी के कई दौरों से होकर गुजरना पड़ता है.

विदेशी माल खरीदने वालों की भी कोई कमी नहीं है. राष्ट्रीय आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य और वहां के जाने-माने शिक्षकों में से एक कारी मुहम्मद अमीन नवाई का दावा है कि अगर विदेशी ताकतें 'हमें अपने यहां ब्रदर-कुशी पर रोक लगाने का मौका दें' तो यह देश एक बार फिर से अमीर हो जाएगा. अंग्रेजी-अफगानी का मिश्रित शब्द 'ब्रदर-कुशी' काफी चर्चित हो चुका है.

काबुल में सोवियत सैनिकों के लिए कोई रोमांस रचाने वाला नहीं है पर रूसियों की वापसी के बाद होने वाली भयंकर 'ब्रदर-कुशी' के बारे में सोचकर हर कोई चिंतित है. यह तय लग रहा है कि मुजाहिदीन न केवल नजीबुल्लाह की 4 लाख सैनिकों वाली सेना से दो-दो हाथ करेंगे बल्कि उनका आपस में लड़ना भी तय है. इसी तरह नजीब की सेना के खलकी और परचमी गुटों में भी सत्ता के लिए संघर्ष होना निश्चित है. लेकिन बचे-खुचे समझदार अफगानी नेता इन कोशिशों में लगे हुए हैं कि रक्तपात न होने पाए.

नजीब सरकार दुलार और फटकार की नीति पर चलना चाहती है. काबुल में अमन का पैगाम देने भी बख्तरबंद गाड़ियां घूम रही हैं

इसका एक रास्ता तो यह है कि एक ऐसी अंतरिम सरकार बनाई जाए जो कम-से-कम नजीब सरकार की तरह विवादास्पद तो न हो. इस सिलसिले में एक उपाय यह है कि कबीलों का एक 'सरबत खालसा' जैसा सम्मेलन 'लोया जिरगा' आयोजित किया जाए जिसमें सभी प्रमुख अफगानी नेता, सांसद, कबीलों के मुखिया और धार्मिक प्रतिनिधि हिस्सा लें. लेकिन इस बात की संभावनाएं कम हैं कि जब तक नजीब के स्थान पर किसी अधिक लोकप्रिय नेता को तैनात नहीं किया जाता तब तक मुजाहिदीन ऐसे किसी सम्मेलन से दूर ही रहेंगे. इस संदर्भ में अफगानिस्तान के पूर्व शाह ज़हीर शाह का नाम लिया जा रहा है जिन्हें सात नरमपंथी दलों के मुजाहिदीन संगठन में तीन दलों का समर्थन प्राप्त है. ज़हीर शाह इन दिनों निर्वासन भोग रहे हैं. लेकिन जहां तक कट्टरपंथियों की बात है वे शाह का भी विरोध ही करने वाले हैं.

बहरहाल, लगता यही है कि कुछ भी कर लिया जाए, राजनीति में या कबीलावाद में, धर्म में से या राजनैतिक विचारधारा में से, इतिहास में से कोई न कोई ऐसा बहाना तो मिल ही जाएगा कि लड़ाई जारी रखी जा सके और अफगानिस्तान अपने ही इतिहास के शोलों में जलता चला जाए—लगातार.

काबुल के बाहर एक गांव में मतदान केंद्र

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मेरठ

दंगे का दंश और दर्द

साल भर बाद भी कोई कार्रवाई न होने से कई सवाल कायम, स्थिति विस्फोटक

शानदार सैनिक छावनी और 1857 के सिपाही विद्रोह के लिए विख्यात मेरठ आज भारतीय जनजीवन के सबसे बदसूरत पहलू—सांप्रदायिकता—के लिए बदनाम-सा हो गया है. पुलिस ज्यादतियों ने इस बदसूरती को और बढ़ाया ही है. हर शख्स आज लूटपाट व खूंरेजी पर उतारू गुटों और पुलिस की अक्सर होने वाली मनमानी गोलीबारी के कारण दहशत में जी रहा है. पिछले पखवाड़े मवाद एक बार फिर बह पड़ा. पुलिस गोली से एक व्यक्ति मारा गया. यह शहर गाहे-बगाहे तुरंत उबल क्यों पड़ता है? पिछली मई के दंगे के बाद हुई तहकीकात के नतीजों से सरकार क्या कोई सबक ले पाई है? इन सवालों पर वरिष्ठ संवाददाता **पंकज पचौरी** *की रिपोर्ट:*

मेरठ में खूनखराबे का दौर खत्म हुए पूरा एक साल बीत चुका है. तब धर्म के नाम पर हुए नरसंहार के बाद कानून और व्यवस्था के नाम पर भी कइयों को मौत के घाट उतार दिया गया था. मलियाना और हाशिमपुरा अचानक सुर्खियों में आ गए थे. कत्लगाह के पर्याय बन गए थे ये दोनों इलाके. लेकिन उन दिनों आखिर हो क्या गया था? कौन जिम्मेदार था इन सबके लिए? असली अपराधी कौन हैं? सजा किसे दी जाए?

इन सवालों का जवाब आज एक साल बाद भी किसी के पास नहीं है. पूर्व नियंत्रक व महालेखापरीक्षक ज्ञान प्रकाश की, जिन्हें दंगे की विस्तृत जांच का जिम्मा सौंपा गया था, रिपोर्ट अभी तक अधिकारिक तौर पर जारी नहीं की गई है. दंगे से संबंधित तहकीकात भी कछुआ चाल से ही चल रही हैं. और मेरठ पर हिंसा के साये मंडरा रहे हैं. लगता है कि पूरे शहर में बारूद बिखेर दी गई है. एक चिनगारी और बस भयंकर विस्फोट!

मेरठ का वह बदसूरत पहलू पिछले पखवाड़े फिर उजागर हो गया. पुलिस द्वारा दंगाई भीड़ पर गोली चलाने से एक व्यक्ति मारा गया और दो घायल हो गए. तनाव बेवजह नहीं था. पुलिस ने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के स्थानीय नेता यामीन अंसारी को गिरफ्तार कर लिया था. जिला मजिस्ट्रेट विजय शर्मा के अनुसार अंसारी पर भड़काऊ पर्चे बांटकर लोगों को उकसाने के आरोप हैं. उनकी गिरफ्तारी के बाद लगभग 2000 मुसलमानों ने उस थाने को घेर लिया. तनाव बढ़ गया. पुलिस को गोली चलानी पड़ी. और सड़कें पुलिस के हवाले कर दी गईं. कुल मिलाकर शहर की स्थिति पिछले साल जैसी ही बन गई थी.

लगता है पूरे शहर में बारूद बिखेर दी गई है. एक चिनगारी और भयंकर विस्फोट! अफसोस तो यह है कि ज्ञान प्रकाश समिति की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया वरना आज इतना तनाव नहीं होता

मेरठ की सड़कों पर पुलिस गश्त ; और (इनसेट में) ज्ञान प्रकाश

अफसोस की बात यह है कि सरकार ने ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट के सुझावों को लागू नहीं किया वरना शायद हिंसा दुबारा न होती. समिति के प्रमुख सुझाव हैं:

► दंगों के लिए दोषी पाए गए लोगों पर तेजी से मुकदमा चलाने के लिए विशेष अदालतों की स्थापना; शहर में दंगों से निबटने के लिए नई नीति तैयार करना और पुलिस को बेहतर साज-सामान से लैस करना; क्षतिग्रस्त उद्योग और व्यापार को पुनर्जीवित करना ताकि पूंजी बाहर न जाए.

► हिंदू-मुस्लिम झगड़े की जड़— बाबरी मस्जिद-रामजन्मभूमि विवाद— का न्यायिक निबटारा; कट्टरवाद को बढ़ावा देने वाली 'सेनाओं' के गठन पर रोक और गड़बड़ी वाले इलाकों में लाउडस्पीकर पर रोक.

► पुलिस में लोगों का विश्वास जमाने के लिए उसमें अल्पसंख्यकों की भरती की योजना; चुनाव प्रचार के दौरान धार्मिक प्रसंगों के इस्तेमाल पर रोक के लिए विधेयक; स्थानीय नेतृत्व उभारने के लिए नगरपालिका के चुनाव; और शहर के घनी आबादी और गड़बड़ी वाले क्षेत्रों में झोंपड़-पट्टियों को हटाना.

वैसे ये सुझाव भी बहुत मौलिक नहीं हैं. इस नई रिपोर्ट का भी पहले की ऐसी रिपोर्टों जैसा हश्र हो रहा है. मेरठ में आज तक कोई विशेष अदालत नहीं बनाई गई है. और चूंकि स्थानीय प्रशासन को अभी तक लखनऊ से कोई निर्देश नहीं मिला है, सो पिछली मई में हुए दंगों के लिए अब तक एक भी व्यक्ति पर मुकदमा नहीं शुरू हो पाया है. अधिकारियों को तो अब तक यह भी पता नहीं चला है कि पिछले दंगे में

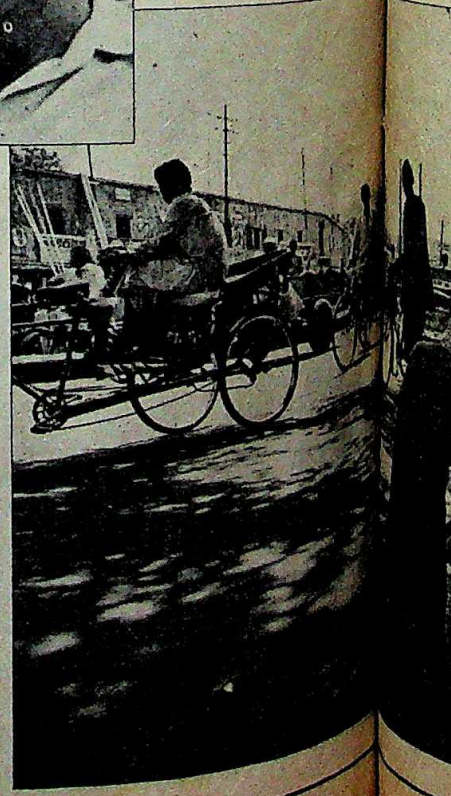

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

में कितने लोग मारे गए. दंगे के एक साल बाद भी मृतकों की तिनाख्त जारी है. हर रोज किसी-न-किसी परिवार को पास के थाने से प्रमाणपत्र मिल रहे हैं कि पिछली मई से लापता उनका बेटा या पति दंगे में मारा गया. इसके बाद ये प्रमाणपत्र मुआवजा पाने के लिए जिला अदालत में दाखिल किए जाते हैं. अब तक ऐसे 160 मामले में मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है

हालांकि ज्ञान प्रकाश समिति ने 117 व्यक्तियों की मौत दर्ज की है, लेकिन इन मामलों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं शुरू की गई है. सरकारी वकीलों का कहना है कि दंगे में अधिकारियों की भूमिका की अलग से जांच की जा रही है. इसलिए कार्रवाई नहीं शुरू की जा सकी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज वी.एस.एल. श्रीवास्तव को मलियाना में अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश देने वाले अधिकारियों की भूमिका की जांच का काम सौंपा गया था. इस जांच आयोग ने अब तक सिर्फ दो ही सुनावाई की है.

इसी तरह की दूसरी जांच सीआईडी के डीआईजी जंगी सिंह कर रहे हैं. उन्हें हाशिमपुरा निवासियों के इस आरोप की जांच का काम सौंपा गया है कि पीएसी वाले निर्दोष लोगों को एक ट्रक में लादकर 25 किलोमीटर दूर नहर के किनारे ले गए और उन्हें गोली से उड़ा दिया. जंगी सिंह दंगे के बाद शहर में चार महीने तक डेरा डाले रहे, 100 से भी ज्यादा चश्मदीदों से उन्होंने बात की. पिछले पखवाड़े उत्तर प्रदेश के गृहमंत्री दीक्षित ने बयान दिया कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है. और यह कि "जनहित में ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट को जारी करना ठीक नहीं होगा."

लेकिन पीएसी के डिप्टी कमांडेंट आर.के. त्रिपाठी को मलियाना गांव में अंधाधुंध गोली चलाने के लिए निलंबित करने के अलावा किसी और अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है. पीएसी की जिस टुकड़ी पर हाशिमपुरा में नरसंहार करने के आरोप हैं उसके प्लाटून कमांडर सुरिंदर सिंह अब तक अपने पद पर जमे हुए हैं. हालांकि ज्ञान प्रकाश रिपोर्ट ने स्वीकार किया है कि "स्थानीय प्रशासन दंगों को रोकने में विफल रहा" लेकिन तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट राधेश्याम कौशिक, डीआईजी नाथू लाल और दूसरे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है.

सरकारी अकर्मण्यता और उदासीनता का असर सब ओर दिखता है. डर और अविश्वास ने मेरठ के निवासियों के मन में घर कर लिया है. मलियाना की 72 वर्षीया नफीस बेगम कहती हैं, "आधे लोग तो यह गांव ही छोड़ कर चले गए हैं. खाकी वर्दी वाले हर शख्स को शक की नजर से देखा जाता है. प्रधानमंत्री आए और चले गए, लेकिन कहीं कुछ नहीं बदला." हाशिमपुरा के 70 वर्षीय मुहम्मद उमर इंतजार का एक पीड़ादायक दौर भुगत चुके हैं. उनके 47 साल के बेटे जमील अहमद और दो पोतों, 14 वर्षीय नसीम और 17 वर्षीय सलीम को दंगों के दौरान पीएसी गिरफ्तार करके ले गई थी. पांच दिन बाद सलीम फतेहगढ़ जेल से अपने पिता के शव के साथ लौटा. लेकिन नसीम आज तक लापता है. हताश उमर बताते हैं, "कितने महीनों से मैं दिल्ली और लखनऊ खत लिख रहा हूं. लेकिन एक ही जवाब मिलता है कि हम आपके पोते की तलाश कर रहे हैं." 27 वर्षीय मुहम्मद उस्मान बताते हैं कि वे गंगा नहर के तट पर पीएसी की गोलियों से किसी प्रकार बच गए थे. नाराजगी से वह कहते हैं, "हमें किसी पुलिसवाले पर भरोसा नहीं."

यही हाल दोनों धार्मिक संप्रदायों का है.

मलियाना की 72 वर्षीया नफीस बेगम कहती हैं, "प्रधानमंत्री यहां आए और चले गए. लेकिन कहीं कुछ भी बदला नहीं"

मेरठ व्यापार संघ के अध्यक्ष ओ.पी. खन्ना साफ-साफ कहते हैं कि मेरठ में पूंजी लगाना अब निरापद नहीं रहा

मु. उस्मान बताते हैं वे गंगा नहर के तट पर पीएसी की गोलियों से किसी तरह बच गए. उन्हें पुलिस पर भरोसा नहीं

प्रमोद पुष्करणा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

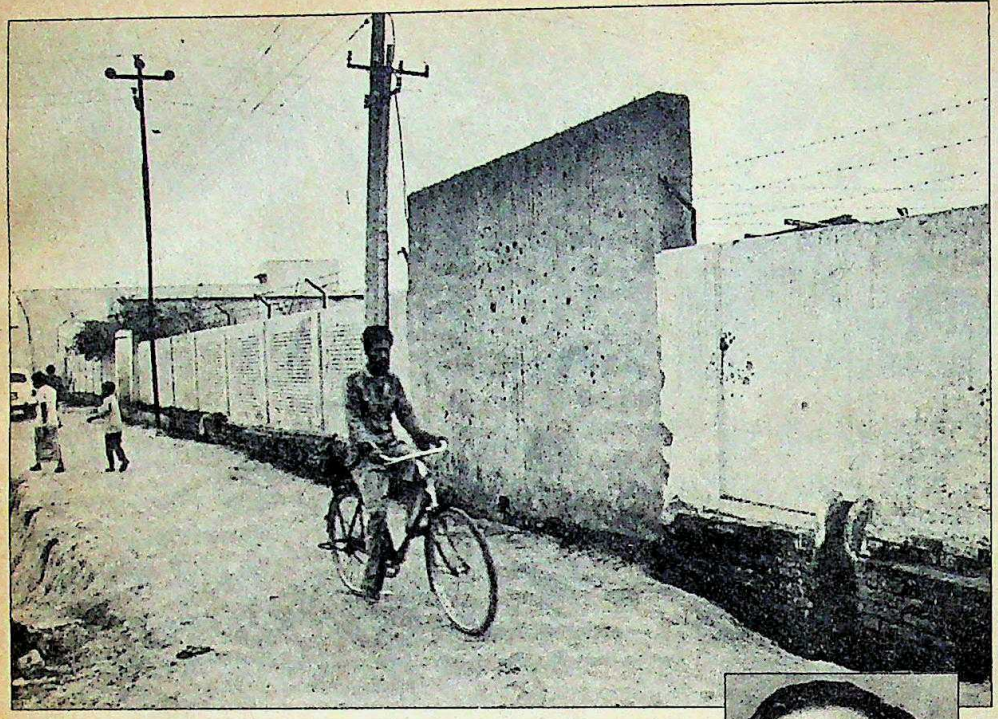

प्रशांत पंजियार

मुस्लिम झोपड़पट्टियों की ओर कारखाने की बंद दीवार; और (इनसेट में) दीवान

मंडल आयुक्त दीवान कहते हैं कि मेरठ की असली बीमारी बाबरी मस्जिद-रामजन्मभूमि विवाद ही है

दोनों का एक दूसरे पर से भरोसा उठ गया है. मेरठ के मंडल आयुक्त वी.के. दीवान कहते हैं, "मेरठ की असली बीमारी बाबरी मस्जिद-रामजन्मभूमि विवाद ही है."

होली के दौरान दोनों संप्रदायों के बीच मेलमिलाप ने वैमनस्य को थोड़े दिनों के लिए कुछ कम तो किया था लेकिन शहर में सांप्रदायिक खेमेबंदी साफ नजर आती है. मसलन पिलोखरी औद्योगिक क्षेत्र के कारखानों के सामने मुस्लिमबहुल झोंपड़पट्टियों की ओर अब दीवार खड़ी कर दी गई है. औद्योगिक क्षेत्र का दरवाजा हिंदू कॉलोनियों की ओर खोल दिया गया है. मेरठ व्यापार संघ के 47 वर्षीय अध्यक्ष ओ.पी. खन्ना साफ-साफ कहते हैं कि "मेरठ में पूंजी लगाना अब निरापद नहीं रह गया है."

ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट के अनुसार पिछले दंगे में लगभग 10 करोड़ रुपए मूल्य की निजी संपत्ति का नुकसान हुआ. लेकिन प्रशासन ने 2516 लोगों के बीच करीब 1.04 करोड़ रुपए मुआवजे के बतौर बांट कर 'मामला खत्म कर दिया है.' सहायक जिला मजिस्ट्रेट (वित्त) रमेश चंदानी कहते हैं, "सरकार के लिए पूरे नुकसान की भरपाई कर पाना असंभव है."

ज्ञान प्रकाश समिति की यह आशंका कि दंगों का व्यापार पर भी असर पड़ेगा, सच साबित हो चली है. इस साल का नौचंदी मेला फीका ही रहा. प्रशासन ने व्यापारियों को आकर्षित करने के लिए स्टॉलों के किराये में 20 प्रतिशत की छूट भी दी लेकिन 10 फीसदी स्टॉल फिर भी खाली ही पड़े रहे. इसके अलावा मेरठ का हथकरघे का शानदार व्यवसाय (वार्षिक कारोबार 600 करोड़ रुपए) भी बिखरने लगा है. अकेले पिलोखरी में ही दंगे के दौरान कपड़ा छपाई के 10 कारखाने जला दिए गए.

सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए ज्ञान प्रकाश समिति ने शहर में नगरपालिका चुनाव कराने का भी सुझाव दिया था. इससे इस शहर की राजनीति का रुख ही बदल जाता, जिस पर इन दिनों कट्टरपंथियों ने कब्जा जमा रखा है. लेकिन यहां तो 1974 के बाद चुनाव हुए ही नहीं हैं. इंकाई सूत्र भी कबूल करते हैं कि पार्टी को डर है कि वह दोबारा जीत नहीं पाएगी. इसलिए चुनाव भी नहीं कराए जाते. एक स्थानीय दैनिक के संपादक अतुल माहेश्वरी ने कहा, "स्थानीय चुनाव कराए गए तो हर गली-मुहल्ले में नेता उभर आएंगे जिनका मतदाताओं पर कुछ तो प्रभाव होगा ही. इससे तनाव कम करने में काफी मदद मिलेगी."

आज पीएसी की 14 कंपनियों ने मेरठ में डेरा जमा रखा है. जिला मजिस्ट्रेट विजय शर्मा ने बताया कि पीएसी की गतिशीलता और संचार सुविधा में पर्याप्त सुधार किया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर वह फुर्ती से कार्रवाई कर सके. पांच नए थाने खोले गए हैं, और दूसरे कई थाने खोलने का विचार किया जा रहा है.

लेकिन सबसे अहम जो चीज है— कार्य-कुशलता और विश्वसनीयता— वह न तो पैसों से खरीदी जा सकती है, न उसकी कमी आधुनिक हथियारों से पूरी की जा सकती है. इसकी भरपाई तभी हो सकती है जब दंगे में हुई हत्याओं की जांच हो और दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाए.

बहरहाल, क्रूर विडंबना तो यही है कि पुलिस मेरठ के लिए अपरिहार्य बन गई है. जैसा कि गृह मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है, "जहां दो संप्रदायों के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हों, वहां और क्या विकल्प बचता है." मेरठ में तैनात एक आईपीएस अधिकारी का कहना है, "आज यहां से पुलिस के दस्ते हटा दिए जाएं तो महीने भर में ही एक और दंगा हो जाएगा."

दुर्भाग्य से इतिहास खुद को मेरठ में दोहराने को मजबूर है, क्योंकि सत्ताधारी राजनीतिक या तो इस समस्या को ठीक-ठीक नहीं समझ पाए हैं या अतीत की घटनाओं से कोई सबक लेने की जरूरत नहीं समझते. इसके अलावा वे उन सुझावों को मानने को भी तैयार नहीं दिखते जो उनके राजनैतिक हितों के खिलाफ जाते हों. तभी तो सरकारी आंकड़े के अनुसार 261 मौतों, तीन-तीन जांच आयोगों और कई-कई आश्वासनों के बावजूद मेरठ आज भी उसी दर्द से कराह रहा है.

—पंकज पचौरी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उदारता की प्रतीक्षा

औद्योगिक नीति, खासकर लाइसेंस नीति को उदार बनाने के सरकारी अभियान की सुस्ती से परेशान लोगों को शायद जल्दी ही कोई खुशखबरी मिले. इन नीतियों को उदार बनाने के जिन प्रस्तावों पर आजकल विचार-विमर्श चल रहा है उनमें इस शिकायत को दूर करने का भी प्रस्ताव है कि अभी तक की उदारता सिर्फ कागजी है, व्यावहारिक नहीं. सरकार खास तौर पर ऐसे उद्योगों की सूची जारी करेगी जिनमें किसी तरह के लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी. हां, उन उद्योगों के लाइसेंस के नियम कड़े होंगे जिनके बारे में सरकार मानती है कि यहां आने वालों को नियंत्रित करने की जरूरत है.

लालभाई के बहुरंगी इरादे

करीब 650 करोड़ रुपए के कारोबार वाला लालभाई समूह बड़े पैमाने पर विस्तार और दूसरे क्षेत्रों में प्रवेश की तैयारी कर रहा है. यह अब इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जे और इंजीनियरिंग प्लास्टिक के क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहा है. वह अगले कुछ वर्षों में कपड़े के कारोबार में 100 करोड़ रुपए का निवेश भी करने जा रहा है जिसमें राजस्थान में ऊनी मिलें लगाना भी शामिल है. उधर वीडियो कैसेट टेप की कोटिंग बनाने की 25 करोड़ की योजना के लिए इस समूह ने जापान की जेवीसी से गठबंधन किया है. फिर 17.5 करोड़ रुपए की रेसीन वाली योजना के लिए यह समूह अमेरिकी और जापानी कंपनियों के साथ गठबंधन की बातचीत चला रहा है. यह सब करने से बिक्री में कितनी वृद्धि होगी यह स्पष्ट तो नहीं है, पर उम्मीद है कि इस समूह के कारोबार में अगले साल 100 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हो जाएगी.

तिपहियों पर जोर

भारतीय ऑटोमोबाइल्स बाजार पर जापानी 'हमले' का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है. एस्कोर्ट्स के साथ दुपहिया वाहनों के उत्पादन का गठबंधन करने के बाद यामाहा ने बंबई की ऑटोमोबाइल्स प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया (एपीआई) के साथ तिपहिया वाहन बनाने के लिए गठबंधन किया है. एपीआई जब लैंब्रेटा स्कूटर्स बना रही थी तो देश की दुपहिया वाहन कंपनियों में अगुआ थी, लेकिन हाल में इसने स्कूटर का अपना कारोबार कम कर दिया है. अब इसने अपने तिपहियों में यामाहा इंजन लगाकर इनका कारोबार बढ़ाने का फैसला किया है. चार स्ट्रोक वाला यह इंजन ईंधन की कम खपत करता है. इसका कम कीमत वाला एक छोटा स्कूटर (मोपेड की कीमतों में) भी बाजार में आ सकता है.

मिनी शहंशाह बन बैठे

राज्यों में औद्योगिक विकास निगमों के चमक-दमक वाले दिन शायद लद गए हैं. पिछले दशक में इन निगमों ने ढेर सारे औद्योगिक लाइसेंस लिए, फिर उन्हें निजी क्षेत्रों को बेच दिया, शेयर में भागीदारी के आधार पर संयुक्त क्षेत्र में कंपनियां लगाईं और अपने-अपने राज्यों में औद्योगिक विकास के मामले में मिनी शहंशाह बन बैठे. लेकिन अब केंद्र सरकार को लग गया है कि ये निगम औद्योगिक लाइसेंस हथियाकर उन्हें ऊंची कीमत पर बेचने और निजी क्षेत्र की कंपनियों से भी अपने हिस्से के शेयरों का निवेश कराने जैसे कामों के अलावा शायद ही कुछ करते हैं. केंद्र मानता है कि इन निगमों को बीच में लाने के बजाय सीधे उद्यमियों को ही लाइसेंस देना बेहतर है.

निर्यात की नियति

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकानॉमी द्वारा जुटाए गए आंकड़े से पता चलता है कि निर्यात के मामले में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां पिछड़ती ही जा रही हैं. 1973-74 में उनकी ओर से निर्यात 675 करोड़ रुपए मूल्य का हुआ, जो 1986-87 में बढ़कर 3942 करोड़ रुपए तक तो पहुंच गया लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के कुल कारोबार में निर्यात का प्रतिशत 9.9

चार्ट: बी.के. शर्मा

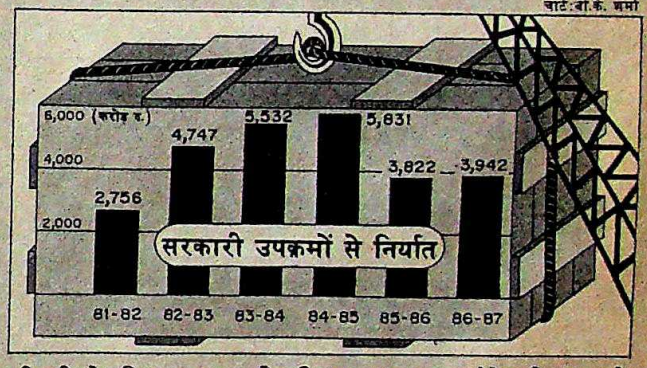

फीसदी से गिरकर 5.7 फीसदी पर आ गया. वैसे भी हाल के वर्षों में कुल निर्यात में भी गिरावट आई है. 1984-85 में यह अधिकतम 5831 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था. गैर-सरणीबद्ध चीजों के निर्यात में अधिक गिरावट आई है. 1983-84 में ऐसा निर्यात 3317 करोड़ रुपए मूल्य का था जो 1986-87 में घट कर मात्र 1285 करोड़ रुपए का हो गया.

सीमा पार संभावनाएं

टेलीविजन उद्योग को एकाएक निर्यात की काफी संभावनाएं नजर आने लगी हैं. मौजूदा उत्पादन के बराबर यानी करीब 40 लाख श्वेत-श्याम सेटों के निर्यात की संभावना दिखने लगी है. अभी तक अमेरिका और यूरोप को ऐसे सेट निर्यात करने वाले दक्षिण कोरिया ने इनका उत्पादन बंद करके अधिक मुनाफा देने वाले रंगीन सेट बनाना शुरू कर दिया है. इसलिए टेलिविस्टा, डायनोरा और क्राउन कंपनियां अब एक निर्यात समूह बनाने की बात करने लगी हैं. टेलिविस्टा ने तो पिक्चर ट्यूब बनाने वाली कंपनी सैमटेल के साथ मिलकर एक नई कंपनी बनाने की बात भी शुरू कर दी है जो सिर्फ निर्यात के लिए ही माल बनाएगी. जिन दूसरी संभावनाओं पर बात हो रही है उनमें सार्वजनिक क्षेत्र के 'ईटी ऐंड टी' को निर्यात के मामले में अगुआ बनाना शामिल है. लेकिन यह सब आसान नहीं है. इसके लिए उत्पादन क्षमता बढ़ानी होगी. सेटों की तकनीकी अपेक्षाओं के मामले में यूरोप व अमेरिका और भारत के बाजार की मांगें काफी अलग हैं.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

व्यवसाय जगत

प्रतिस्पर्धा से हालत पतली

अब उत्पादकों की नहीं बल्कि उपभोक्ताओं की चलती है

पहले सिर्फ लाइसेंस दिए जाते थे. बाद में उदारता बरती जाने लगी. लेकिन अब प्रतिस्पर्धा होने लगी और कंपनियों की आमदनी भी तेजी से गिरने लगी. इस तरह भारतीय व्यवसाय की दुनिया ही बदल गई.

किसी समय, सरकार से औद्योगिक लाइसेंस हासिल कर लेने का मतलब होता था मोटी आमदनी का पासपोर्ट मिल जाना. फिर इस मामले में उदारता बरती जाने से पूंजी निवेश और उत्पादन क्षमता बढ़ी. नतीजा आज यह है कि बाजार की बनावट बदल जाने के कारण पूरा का पूरा व्यावसायिक माहौल ही नया हो गया है: पहले बाजार में किल्लत रहती थी, अब माल की भरमार हो गई है; पहले विक्रेता खरीदारों पर हावी रहते थे, अब ग्राहकों के सामने कई विकल्प हैं.

प्रतिस्पर्धा का दंश हर कोई महसूस कर रहा है: कंपनियां कीमतें घटा रही हैं, लागत कम कर रहीं हैं, अवांछित मजदूरों को अलविदा कह रही हैं और निर्यात बाजार में घुसपैठ के लिए तेजी से हाथ पैर मार रही हैं. जो कमजोर या अक्षम हैं, उनकी किस्मत में समाप्त होना ही बदा है.

बंबई स्थित अरिधि इन्वेस्टमेंट्स कंसल्टेंट्स के प्रबंध निदेशक एम.के. पिपरैया कहते हैं, "भारतीय उद्योग का माहौल बिलकुल बदल गया है. बाजार पहले के मुकाबले ज्यादा खुला हो गया है, आयात से होड़ बढ़ गई है, नई तकनीक तेजी से इस्तेमाल में लाई जा रही है और इससे जो अतिरिक्त उत्पादन क्षमता बढ़ी है, उससे स्पर्धा तेज हो गई है."

कंपनियों का लाभ तेजी से घटने के आंकड़े खुद अपनी कहानी कहते हैं. देश के निजी क्षेत्र की दस सबसे बड़ी कंपनियों में से नौ का लेखाजोखा 1986-87 में लाभ घटने की बात कबूल करता है. लाभ घटने वाली इन कंपनियों में टिस्को, टेल्को, रिलायंस इंडस्ट्रीज और एसोसिएटेड सीमेंट भी हैं. अपवाद सिर्फ गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर कंपनी है.

सौ बड़ी कंपनियों के आंकड़े भी नाटकीय हैं. इन कंपनियों ने 1986-87 में लगभग 9 फीसदी ज्यादा माल बेचा लेकिन उनकी आमदनी में इस साल 24.3 फीसदी की कमी आई. मजेदार बात तो यह है यह सब उद्योगों के तेजी से हो रहे विकास के दौरान हुआ जब लाभ आम तौर पर बढ़ता है. नए पूंजी निवेश और उत्पादन क्षमता के कारण उद्योगों का बहुत विकास तो हुआ लेकिन होड़ बढ़ने से लाभ में कमी आई.

लेकिन कंपनियों और निवेशकों के नुकसान से उपभोक्ताओं को फायदा हुआ है. आज सीमेंट के दाम वही हैं जो छह साल पहले थे. यही स्थिति उर्वरकों की भी है. स्कूटरों और सिंथेटिक कपड़ों की कीमतें भी बहुत कम बढ़ी हैं. यदि आमदनी कम हो रही है तो इसकी वजह कीमतों का कम होना है.

लाभ में कमी आना ऐसे समय शुरू हुआ है जब कंपनियां ज्यादा प्रतिस्पर्धा वाले बाजार में टिके रहने के लिए आधुनिकीकरण पर भारी-भरकम रकम खर्च करने पर मजबूर हो रही हैं. नतीजा यह है कि उन पर दोहरी मार पड़ रही है—ब्याज का बढ़ता बोझ और घिसाई के कारण मशीनों का मूल्यह्रास.

बंबई स्थित आंकड़े इकट्ठा करने वाली इकाई—सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकानॉमी (सीएमआईई) की गणना के मुताबिक कंपनी क्षेत्र में शेयर राशि में हुई बढ़ोतरी पर ब्याज का बोझ 1982-83 के 21 फीसदी से बढ़कर चार साल बाद 25 फीसदी हो गया. लेकिन इसी अवधि में लाभ 8.9 फीसदी से घटकर 6.6 फीसदी हो गया था.

लाभ कम होने और ब्याज की दरें बढ़ने के कारण दोहरी मार तो पड़ी ही है, एक तीसरी मार भी पड़ी है: चूंकि कंपनियों को अपने शेयर और डिबेंचर जारी करने के लिए शेयर बाजार पर निर्भर रहना पड़ता है, लिहाजा कई कंपनियां लाभ कम हो जाने के बावजूद पूंजी निवेशकों को भारी लाभांश देकर खुश रखने की कोशिश करती रहीं. लाभ घटने के

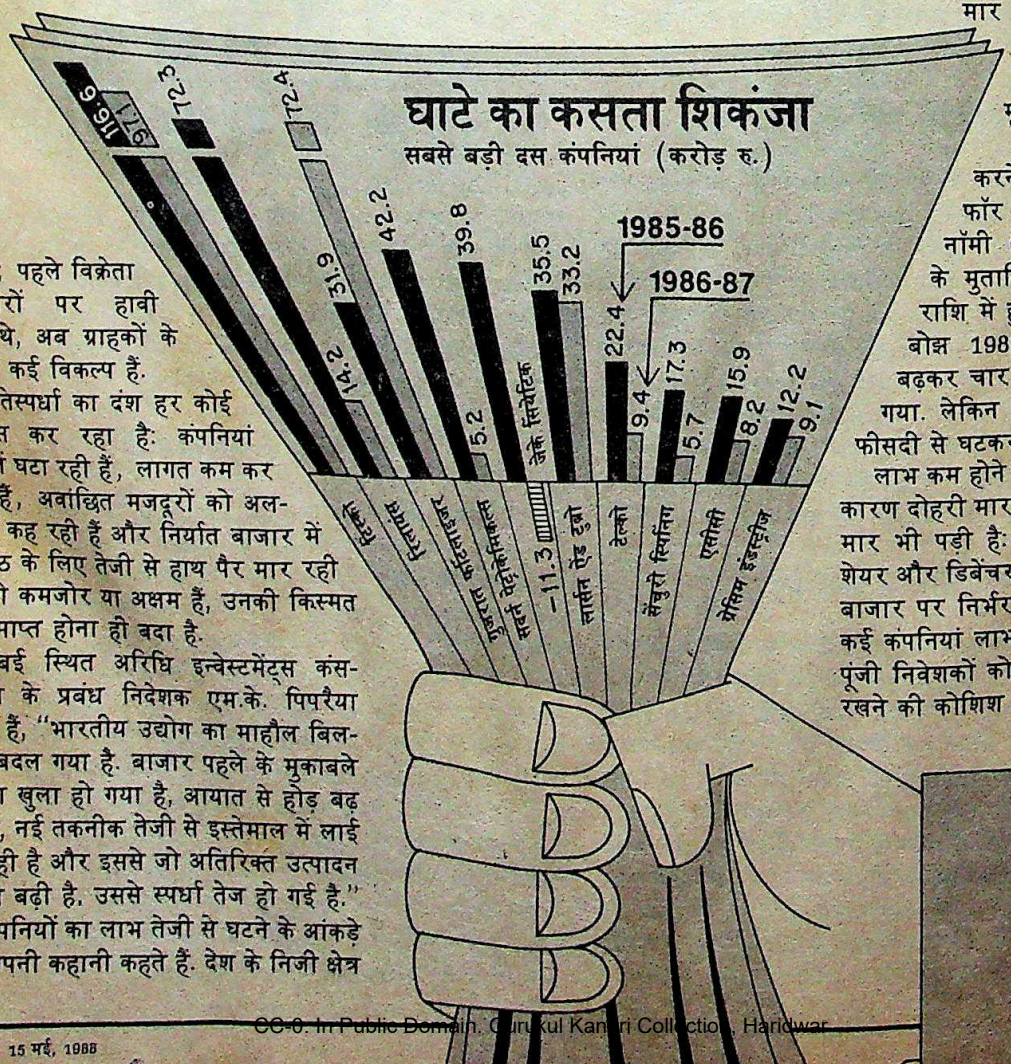

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"भारतीय उद्योगों का माहौल बिलकुल बदल गया है और यहां आपसी प्रतिद्वंद्विता बहुत बढ़ गई है."

राम के. पिपरैया
प्रबंध निदेशक,
अरिधि इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स

"निस्संदेह कई क्षेत्रों में खरीदारों का बाजार उभर आया है. अब बाजार में किसी चीज की कमी नहीं रह गई है"

बी.के. मोदी
प्रबंध निदेशक,
मोदी रबर

बावजूद 1986-87 में कंपनियों की ओर से दिया जाने वाला लाभांश 30 फीसदी से ज्यादा पहुंच गया.

व्यावसायिक जगत इस बात को मानता है कि नया माहौल सरकार द्वारा '80 के शुरू में नीति को उदार बनाने के लिए शुरू की गई प्रक्रिया का ही नतीजा है. यह प्रक्रिया 1985 के और भी तेज हो गई जब सरकार नाटकीय ढंग से अधिक संख्या में लाइसेंस देने लगी, विदेशी सहयोगों पर दस्तखत होने लगे और पूंजी बाजार में उफान आया. इसके कुछ स्पष्ट नतीजे सामने आए:

- उद्योग के कई क्षेत्रों में निर्माताओं की संख्या बढ़ गई है. दुपहिया वाहनों के क्षेत्र में छह से 15, पोलिएस्टर धागे और कपड़े के क्षेत्र में छह से 24, कार के क्षेत्र में दो से सात और टेलीफोन उपकरण के क्षेत्र में निर्माताओं की संख्या एक से कई दर्जन हो गई है.
- जिन वस्तुओं की कमी थी, उनकी बाढ़ आ गई. एक दशक पहले स्कूटर, कार, या टेलीफोन लेने के लिए लाइन लगानी पड़ती थी. सीमेंट और टायर मुख्यतः काला बाजार में मिलते थे. पोलिएस्टर भी काले बाजार में बिकता था. हर चीज की बहुत कम सप्लाई थी. लेकिन अब सीमेंट कहीं भी आसानी से उपलब्ध है, उर्वरक कंपनियों में खाद के दाम घटाने की होड़ लगी हुई है, दुपहिया कंपनियों को ग्राहक नहीं मिल रहे हैं और कारों की कालाबाजारी खत्म हो गई है. इसी तरह, केबलों, चीनी मिट्टी चादरों, पोलिएस्टर फिल्मों की भी जल्दी ही बाढ़ आ जाएगी और ये चीजें आसानी से मिलने लगेंगी.

स्पष्ट है, भारतीय बाजार की प्रकृति बदल रही है. अब उत्पादकों की नहीं, उपभोक्ताओं की चलती है, टायर, फोटोकॉपियर मशीन और कंप्यूटर का व्यवसाय करने वाले बी.के. मोदी कहते हैं, "इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कई क्षेत्रों में खरीदारों का बाजार उभर आया है. अब किसी चीज की कमी नहीं है." फॉर्बेस कंपनी समूह के अध्यक्ष एफ.ए. मेहता पुष्टि करते हैं, "एक के बाद दूसरे क्षेत्र से गिने-चुने निर्माताओं का प्रभुत्व खत्म होता जा रहा है."

अब उपभोक्ताओं के पास विकल्प हैं और वे अपनी पसंद की चीजें खरीद सकते हैं. चाहे डिब्बाबंद खाना हो, टीवी सेट, कंप्यूटर, फोटोकॉपिइंग मशीनें, टेलीफोन के उपकरण, दुपहिया गाड़ियां, साबुन हों या पूंजी लगाने के तरीके, सबके विकल्प आज मौजूद हैं. दशकों पहले सिर्फ हिंदुस्तान लीवर और टाटा ऑयल साबुन बनाते थे लेकिन अब बाजार में ओसवाल, निरमा, शॉ वैलेस और कर्नाटक सोप्स के भी हैं. बाजार में हर समय नए-नए साबुन आ रहे हैं. एक समय था जब उपभोक्ता को डालडा और रथ में से ही एक को चुनना पड़ता था. लेकिन अब तरह-तरह के खाने के तेल उपलब्ध हैं.

द्वारिका सीमेंट कारखाना: भरपूर क्षमता

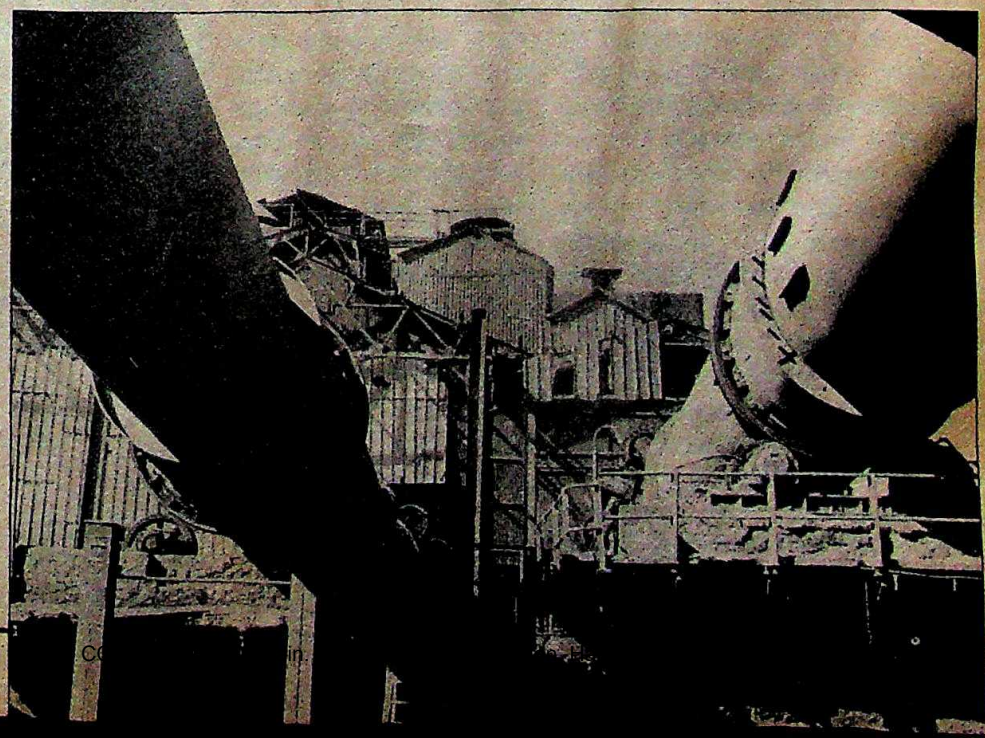

सरकार द्वारा आयात नीति उदार बना देने से भी प्रतिस्पर्धा बढ़ गई. 1986-87 में पूंजीगत सामान का आयात 27.6 फीसदी बढ़ गया. हाल में सरकार द्वारा ओपन जनरल लाइसेंस पर टायर के आयात की अनुमति दे दिए जाने से टायर उद्योग अब चीख-पुकार मचा रहा है. जाहिर है, आयात प्रतिस्पर्धा का एक नया क्षेत्र है और इससे घरेलू उद्योगों का लाभ मारा जा रहा है. निर्माता अब बंदरगाहों में आने वाली वस्तुओं और उनकी कीमतों का पता लगाते रहते हैं.

अब फिजूलखर्ची का जमाना गया. कंपनियां अब पहले जैसा पूंजी निवेश नहीं कर रही हैं. पिछले साल निजी क्षेत्र ने शेयर और डिबेंचरों के जरिये 1,547 करोड़ रुपए उठाए थे जबकि इससे पहले साल में 2,325 करोड़ रुपए मिले थे. जे.एम. फाइनेंस ऐंड इन्वेस्टमेंट के प्रबंध निदेशक निमेश कंपानी कहते हैं, "कंपनियों ने अपना निवेश अभियान धीमा कर दिया है. आप ही बताएं, पूंजी बाजार में उफान कहां है?"

इसी बीच बाजार में प्रतिद्वंद्विता बढ़ने से दो बातें हुईं: कमजोर कंपनियां मैदान से हट

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"कंपनियों ने अपना निवेश अभियान धीमा कर दिया है. पूंजी बाजार में आया उफान अब रहा कहां?"

निमेश कंपानी
प्रबंध निदेशक,
जे.एम.फाइनेंस ऐंड इन्वेस्टमेंट

"एक के बाद दूसरे क्षेत्र से गिने-चुने उत्पादकों का प्रभुत्व खत्म होता जा रहा है. उत्पादकों की भीड़ लग गई है"

एफ.ए. मेहता
अध्यक्ष,
फॉर्बेस समूह

गईं और मजबूत कंपनियों को भी अपना कामकाज अधिक व्यवस्थित करना पड़ा. दुपहिया वाहन उद्योग की कई कंपनियों ने कारोबार समेट लिया या एकदम खस्ता हालत में पहुंच गईं. बंगलूर की श्री चामुंडी मोपेड्स, बंबई की (लैंब्रेटा बनाने वाली) ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स, अवंति गरेली बनाने वाली केल्विनेटर और स्कूटर्स इंडिया ऐसी ही कंपनियां हैं. कंप्यूटर बाजार से दर्जनों कंपनियों को विदा लेनी पड़ी. चौगुले जैसे बड़े घराने ने जापान की कैनन कंपनी के गठबंधन से फोटोकॉपियर बनाने का कारोबार शुरू किया था पर एक तरह से उसका यह कारोबार बंद हो गया है. अभी तक टाइपराइटर का पर्याय बना रेमिंगटन अगर इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर बनाने की तरफ कामयाब कदम न बढ़ाता तो उसका भविष्य भी अंधकारमय ही है. व्यावसायिक वाहनों में स्टैंडर्ड 20 और महिंद्रा की गाड़ियों की बाजार में हिस्सेदारी में नाटकीय गिरावट आई है. निरलॉन ने पॉलिएस्टर का अपना कारोबार बंद कर दिया है और निश्चित रूप से कई और कंपनियों की यही नियति होगी. इंजीनियरिंग उद्योग में तो कठिनाइयों से घिरी या बंद पड़ी कंपनियों की गिनती भी नहीं की जा सकती. एसीसी बाबकाक, मशीनरी मैन्यूफैक्चरर्स कार्पोरेशन और मफतलाल इंजीनियरिंग ऐसी ही कंपनियां हैं.

बाजार में क्वालिटी पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है इसलिए अब कंपनियां भारतीय बाजार पर कब्जा करने की महत्वाकांक्षा रखती हों उन्हें 'क्वालिटी कंपनी' बनना होगा. कपड़ा उद्योग में भी निर्यातोन्मुख कंपनियों का कामकाज ही बढ़िया है.

एक ओर कंपनियों के पिछड़ने का क्रम जारी है और दूसरी ओर छोटे स्तर की वे कंपनियां हैं जो अपना कामकाज व्यवस्थित करके आगे आने वाली मुसीबतों से निबटने के लिए कमर कस रही हैं. कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को अलविदा करने की आकर्षक योजनाएं रख रही हैं, और कर्मचारियों की संख्या और वेतन की रकम घटाने के लिए स्वैच्छिक अवकाश योजनाएं चला रही हैं. इस सूची में टिस्को, टेल्को, एस्कॉर्ट्स, ईआईडी पैरी, रैलीज, मेटल बॉक्स, क्रांप्टन ग्रीव्स वगैरह शामिल हैं. स्वैच्छिक अवकाश योजना लागू करने के बाद इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड को वेतन के मद में हर साल 14 करोड़ रुपए की बचत की उम्मीद है. एसीसी ने इस साल अपने 27,000 कर्मचारियों में से ढाई हजार को अलविदा कहने का फैसला किया है. एसीसी के कार्यकारी उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बी.के. बनर्जी कहते हैं, "दुनिया भर में किफायत और कुशलता बढ़ाने का दौर चल रहा है और अब यह हवा भारत में भी आ पहुंची है. एसीसी को इसी के अनुरूप अपने में बदलाव करना ही होगा."

बाजार में प्रतिद्वंद्विता बढ़ने से पहले की बड़ी कंपनियों की क्या स्थिति हुई है, एसीसी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है. प्रतिस्पर्धा से संकट में पड़ी यह कंपनी अब मजदूरी और ऊर्जा का खर्च घटाने तथा तकनीकी कुशलता बढ़ाने जैसे तमाम गुर आजमा रही है. कंपनी ने उत्प्रेरक बनाने वाली एक इकाई और गुजरात के दो न चल सकने वाले सीमेंट कारखाने बेच दिए हैं. कंपनी अपने और दो या तीन सीमेंट कारखाने बेचना चाहती है क्योंकि वह मानती है कि इन्हें वह फायदेमंद ढंग से नहीं चला सकती. बाकी के कुछ कारखानों को आधुनिक बनाया जाएगा और उनकी कुशलता बढ़ाई जाएगी. साथ ही उनके उत्पादन की विधि बदली जाएगी. मजदूरों की संख्या भी काफी कम कर दी जाएगी और बनर्जी बताते हैं कि कंपनी के बंबई मुख्यालय का खर्च अब तक 20 फसीदी कम किया जा चुका है.

दूसरा उदाहरण आइशर ट्रैक्टर का है. इसने अपने कामकाज का (पुर्जे और इंजन बनाने तथा जोड़ने) खाका नए सिरे से बनाया है और पिछले एक साल में मजदूरों की संख्या 350 घटा ली है. इन अतिरिक्त मजदूरों को व्यावसायिक वाहन बनाने के नए कारखाने में खपाया गया है. इससे एक करोड़ रुपए की वार्षिक बचत हुई है. कई ट्रैक्टर कंपनियों ने भी ऐसा ही किया है.

लेकिन यह तरीका हर बार कारगर साबित नहीं होता और 'अलविदा योजना' के प्रति मजदूर वैसा उत्साह नहीं दिखाते. टिस्को के निदेशक संतोष सिंह कहते हैं, "स्वैच्छिक अवकाश योजना पर हमें अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली क्योंकि हमारे मजदूरों को वेतन के अलावा कई सुविधाएं भी मिलती हैं."

फिर भी कई कंपनियों के लिए लागत खर्च घटाना अनिवार्य हो जाएगा और मजदूरी का

दुपहिया वाहनः विकल्प कई

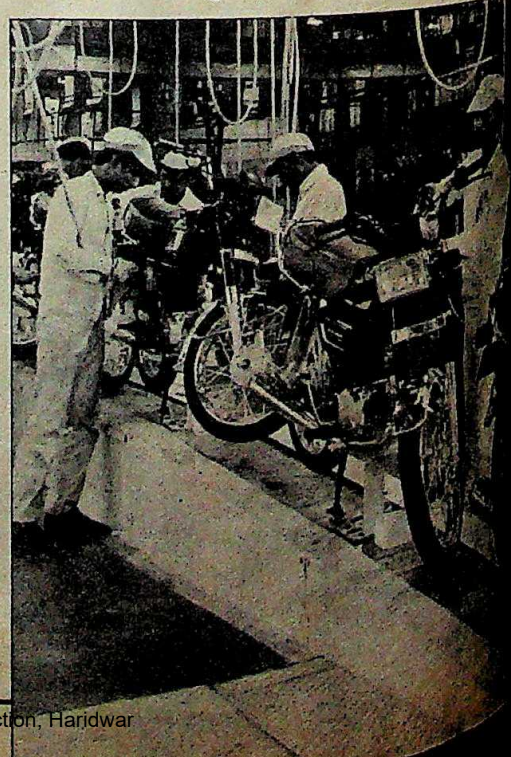

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"बाजार की प्रतिद्वंद्विता ने हमें कार्यकुशलता अभियान चलाने पर मजबूर किया. जापानी सॉफ्टवेयर से भी इसमें मदद मिली"

सुबोध भार्गव
मुख्य अधिकारी, आइशर मोटर्स

"दुनिया भर में कुशलता बढ़ाने का दौर चल रहा है. यह हवा भारत में भी चल पड़ी है. एसीसी को बदलाव करना ही होगा"

बी.के. बनर्जी
कार्यकारी उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, एसीसी

खर्च कम करना इसका एक हिस्सा भर होगा. हिंदुस्तान लीवर हर साल अपने माल के लागत खर्च में एक या दो प्रतिशत की कमी करती थी. अब कई कंपनियां ऐसा ही कर रही हैं. इसी सिलसिले में कारखाने को आधुनिक बनाने, ऊर्जा की बचत योजनाओं में पूंजी लगाने या कच्चे माल का बेहतर इस्तेमाल करने और बाजार में बेहतर स्थिति बनाने के लिए ज्यादा आधुनिक तकनीक अपनाने का क्रम जारी है.

दरअसल अब पूंजी निवेश के मामले में भी कंपनियां ज्यादा सावधान होती जा रही हैं. बंबई की एक बड़ी कंपनी के व्यावसायिक निदेशक बताते हैं कि अभी हाल तक यह कहना फैशन था कि, "मैं 300 करोड़ रु. का निवेश कर रहा हूं, मैंने 25,000 लोगों को रोजगार दिया है या मेरे यहां कभी हड़ताल नहीं हुई." वे कहते हैं कि आज कंपनियां कहती हैं, "क्या हम इतना निवेश कर सकते हैं या इससे कम में भी काम चलेगा? क्या हम अपने मजदूरों की संख्या घटा सकते हैं?"

आइशर मोटर्स को जैसे ही लगा कि व्यावसायिक वाहन उद्योग में तीखी प्रतिद्वंद्विता होने वाली है, उसने ज्यादा निवेश की योजना बंद कर दी. उसने निर्माण प्रक्रिया को लचीला बनाया, खर्च कम करने की कोशिश की. कंपनी के मुख्य अधिकारी सुबोध भार्गव स्वीकार करते हैं, "प्रतिद्वंद्विता ने हमें ये कदम उठाने पर बाध्य किया और इसमें जापानी सॉफ्टवेयर से भी मदद मिली." दूसरी कंपनियां भी ऐसा ही कर रही हैं. जैसे महिंद्रा ऐंड महिंद्रा ने खर्च घटाने और संगठन को ज्यादा कार्यकुशल बनाने के मकसद से संगठन के पुनर्गठन के लिए प्रबंध सलाहकर्ताओं की मदद ली है.

होड़ बढ़ने का एक और नतीजा यह हुआ कि कंपनियों के लिए विपणन का महत्व बढ़ गया. दस साल पहले बजाज ऑटो के पास कोई बिक्री दस्ता नहीं था, न ही कंपनी कोई विज्ञापन अभियान चलाती थी. रिलायंस इंडस्ट्रीज के कार्यकारी निदेशक अनिल अंबानी बताते हैं कि पॉलिएस्टर धागा बेचने के लिए उनकी कंपनी के बिक्री दस्ते में कुल जमा चार या पांच लोग थे. एसीसी को मालूम ही नहीं था कि बिक्री के लिए क्या किया जाए क्योंकि बाजार में हमेशा ही सीमेंट की कमी रही.

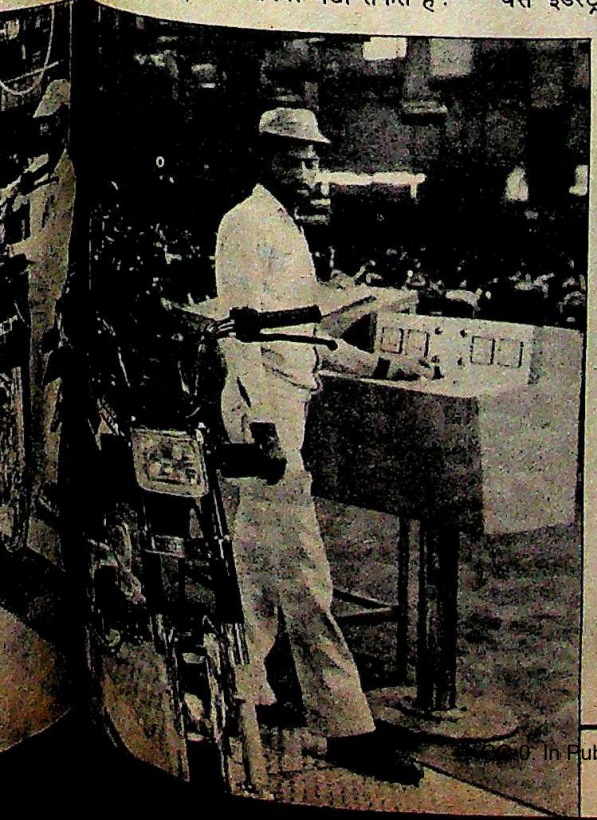

लेकिन आज हालात बिलकुल ही अलग हैं. बजाज ऑटो ने तो देश की तकरीबन आधी पत्रिकाओं का पिछला कवर विज्ञापन के लिए बुक करवा लिया है और वह भी 21वीं सदी तक के लिए. रिलायंस ने बिक्री के अपने अमले में 150 लोग भर्ती कर लिए हैं और इस बात का पक्का इंतजाम कर दिया है कि देश के हरेक पावरलूम केंद्र के लिए एक सेल्समैन हो. एसीसी ने अपने बिक्री विभाग में तकरीबन सभी का स्तर बढ़ाने और तरक्की देने का फैसला कर लिया है.

इस बीच कुछ विशेषज्ञों ने भविष्यवाणी की है कि व्यापारिक मिल्कियत के ढांचों में फेरबदल होना अब लगभग तय है. हालांकि कमजोर कंपनियां धीरे-धीरे किनारे लगती गई हैं फिर भी बीमार उद्योग अब भी बड़ी समस्या बने हुए हैं. उनके आंकड़े खुद उनकी कहानी बता देते हैं. पिछले छह सालों में बीमार उद्योगों की संख्या छह गुना बढ़ी. ऐसे उद्योग 25,000 से बढ़कर 1,50,000 हो गए हैं. औद्योगिक ढांचे में दूसरा फेरबदल उद्योगों के विलय और अधिग्रहण के रूप में होगा. आर.पी. गोयनका का घराना निरलॉन के अधिग्रहण की कोशिश पहले ही कर चुका है, स्कूटर्स इंडिया बजाज को सौंपी जा रही और एस्कॉर्ट्स शायद आंध्र प्रदेश स्कूटर्स को हासिल कर लेगा.

दरअसल बाजार में होड़ तेज हो जाने से उद्योगों की बीमारी को अब एक नया आयाम मिल गया है. अब तक वही औद्योगिक इकाइयां बीमार होती थीं जो या तो आधुनिकीकरण में नाकामयाब रहीं या जिनका प्रबंधन काफी दोषपूर्ण था. अब बीमार उद्योगों की एक नई श्रेणी बन गई है—ऐसे उद्योग जो नए तो हैं पर प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर सकते. इस तरह के बीमार उद्योगों की संख्या भी अभी बढ़ेगी.

अब यह विचार जोर पकड़ता जा रहा है कि बीमार इकाइयों को कारोबार समेटने की इजाजत देने के लिए एक नई नीति बनानी चाहिए. एपीजे समूह के अध्यक्ष सुरेंद्रपाल कहते हैं, "चाहे इकाई कपड़े की हो, जूट की या इंजीनियरिंग की, हर उद्योग में से कुछ इकाइयों को बंद होने की इजाजत मिलनी चाहिए. कमजोर इकाइयों की कुर्बानी पर ही तो बाकी इकाइयां फलेंगी-फूलेंगी."

निश्चित रूप से कामयाब कंपनियों को आर्थिक रूप से फायदेमंद उत्पादन का स्तर हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए. अब

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"हर उद्योग में कुछ इकाइयों को बंद होने की इजाजत मिलनी चाहिए. इससे ही बाकी इकाइयां फले-फूलेंगी"

सुरेंद्र पाल
अध्यक्ष,
एपीजे समूह

"हमारा अनुमान है कि आने वाले समय में कुल मिलाकर मुनाफे की स्थिति में कोई ज्यादा सुधार नहीं होने वाला"

एन. वाघुल
अध्यक्ष,
आईसीआईसीआई

तक तो यह स्तर उनसे दूर ही रहा है. दस साल पहले तक देश में दुपहिया वाहन बनाने वाली कोई भी ऐसी कंपनी नहीं थी जो साल में एक लाख से ज्यादा वाहन बनाती हो. अब बजाज ऑटो ने हर साल 10 लाख वाहन बनाने की इजाजत मांगी है. यह पिछली क्षमता का दस गुना है और उत्पादन के विश्व स्तर के बराबर भी. अब तक भारत की औसत दर्जे की कोई भी कार कंपनी साल भर में 20,000 गाड़ियां बनाती थी. पर पिछले साल मारुति ने 90,000 गाड़ियां बनाईं. पॉलिएस्टर कंपनियां साल में 4,000 टन रेशे बनाती थीं. अब एक इकाई में ही 60,000 टन रेशे बनते हैं. टीवी और कंप्यूटर बनाने वाले भी इसी राह पर चल पड़ेंगे. इस सबके पूरे कार्य-व्यापार का मकसद अब उत्पादन बढ़ाना ही हो गया है. और इसी से उम्मीद बंधी है कि भारतीय उद्योग अब अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा में शामिल हो सकेंगे. हिंदुस्तान लीवर के अध्यक्ष अशोक गांगुली का दावा है कि अगले 10 साल में भारत के 30 से 40 फीसदी उद्योग अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा के काबिल हो जाएंगे और निर्यात भी करने लगेंगे.

वास्तव में दर्जनों कंपनियां इस समय निर्यात बाजार में घुसने की कोशिश कर रही हैं, कुछ तो इसलिए कि यह अब मरने-जीने का सवाल बन गया है और कुछ इसलिए भी कि यह आकर्षक भी है और फायदेमंद भी. रिलायंस लीनियर एल्काइल बेंजीन का निर्यात कर रहा है, कई साल तक मंदी झेलने के बाद टायर कंपनियां भी निर्यात की ओर बढ़ी हैं, और यहां तक कि नए और समस्याग्रस्त वाहन उत्पादक भी विदेशी बाजार में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं.

सवाल यह है कि क्या ये परिवर्तन अंतिम हैं या यह परिवर्तन का एक दौर भर है जो मांग तथा पूर्ति का संतुलन फिर बदलते ही थम जाएगा. आइशर के सुबोध भार्गव कहते हैं, "मूल नजरिया अभी नहीं बदला. जब तक स्पर्धा तेज रहेगी तभी तक ज्यादा कुशलता हासिल करने की कोशिशें भी होंगी. अगर बाजार में फिर किल्लत पैदा हो गई तो उद्योग खुशी-खुशी अपना पुराना ढर्रा अपना लेंगे."

हाल के महीनों में मुनाफे की स्थितियों की वापसी के कुछ संकेत जरूर मिले हैं पर विशेषज्ञ कहते हैं कि इसकी मात्रा बहुत कम है और मुनाफा वृद्धि कुछ ही उद्योगों में है. सीएमआईई के कपाड़िया कहते हैं कि पिछले वर्ष का मुनाफा निचले स्तर पर ही स्थिर रहेगा. पर कई लोग आशावादी भी हैं. रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर सी. रंगराजन कहते हैं, "अगर बिक्री और उत्पादन की बढ़त जारी रही तो कंपनियों का कामकाज अच्छा ही रहेगा."

उर्वरक उद्योग जैसे जरूरत से ज्यादा उत्पादन वाले क्षेत्र में मुनाफे के हालात बदतर होते जा रहे हैं. भारतीय उर्वरक संघ के निदेशक एस.पी. गुप्ता कहते हैं, "1987-88 का लेखा वर्ष हमारे उद्योग के लिए पिछले साल से भी खराब साबित होगा. और पूरा उद्योग घाटे में रहेगा." इंडस्ट्रियल क्रेडिट ऐंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एन. वाघुल का कहना है, "हमारा अनुमान है कि कुल मिलाकर मुनाफे की स्थिति में कोई ज्यादा सुधार नहीं होने जा रहा है."

इसलिए इस बात में संदेह नहीं कि कंपनियों की वित्तीय हालत पहले के मुकाबले काफी पतली है. भारतीय उद्योग विकास बैंक के एक विशेषज्ञ का कहना है कि खरीदारों का बाजार नहीं बदलेगा क्योंकि बहुत सारे उद्योगों ने अत्यधिक उत्पादन क्षमता हासिल कर ली है. अगर यह सच है तो औद्योगिक नीति उदार बनाने की प्रक्रिया में किए गए वायदों में से कुछ तो पूरे होने चाहिए. जैसे ज्यादा प्रतिस्पर्धा, आर्थिक दृष्टि से फायदेमंद उत्पादन का बढ़ा हुआ स्तर, लागत में असरदार कमी और उपभोक्ता के लिए बेहतर सेवा. दूसरी ओर कंपनियां या तो कम मुनाफे में ही जीना सीख लेंगी या मुनाफा बढ़ाने के लिए लागत कम करने की कोशिश में जी-तोड़ मेहनत करेंगी.

—टी.एन. नाइनन

आइशर लागत पर लगाम

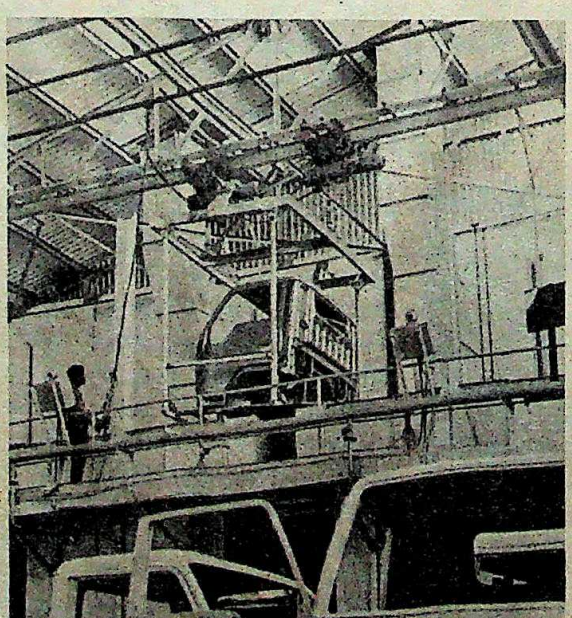

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मेटल बॉक्स

भविष्य डिब्बे में

मालिकों ने हाथ खींच लिए

करीब दो महीने पहले बी.एम. खेतान और उनके बेटे दीपक की बातचीत में आशावादिता दिखती थी. उन्होंने माना कि 136 करोड़ रुपए वाली कंपनी मेटल बॉक्स इंडिया लिमिटेड पर 30 करोड़ रुपए का घाटा चढ़ चुका है, मजदूरी घटाने के प्रस्ताव से कर्मचारी नाराज हैं और मेटल बॉक्स की देश भर की सभी नौ इकाइयां बंद पड़ी हैं. लेकिन बैंकों से 40 करोड़ रुपए का कर्ज मिलने की उम्मीद है और माहौल इतना निराशाजनक भी नहीं है.

फिर भी पिछले पखवाड़े यह 60 वर्षीय मृदुभाषी उद्योगपति और उनका 32 वर्षीय बेटा इस पैकेजिंग और मशीनरी कंपनी के प्रबंधक मंडल से हट गए. सोमवार 18 अप्रैल को कलकत्ता में हुई प्रबंधक मंडल की बैठक में उपाध्यक्ष बी.एम. खेतान और निदेशक दीपक ने अपना इस्तीफा सौंप दिया.

पिछले कुछ महीने इन दोनों के लिए बहुत कठिन रहे. मेटल बॉक्स के उद्धार के लिए उन्होंने कई बार बैंकों और वित्तीय संस्थानों के दरवाजे खटखटाए. दो साल पहले ही वे कंपनी के प्रमुख अंशधारी (33 फीसदी शेयर) इंग्लैंड के मेटल बॉक्स के न्यौते पर कंपनी में शामिल हुए थे.

खेतान परिवार को मजदूर संघों की नाराजगी भी झेलनी पड़ी. कुछ दिनों पहले मेटल बॉक्स यूनियन के करीब 300 सदस्य कलकत्ता स्थित उनके मकान के सामने चार घंटे तक प्रदर्शन करते रहे. मेटल बॉक्स के एक बड़े अधिकारी कहते हैं कि प्रबंधक मंडल में रहने के दौरान खेतान मजदूरों की नाराजगी का निशाना बने हुए थे, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया.

इस्तीफा देने का फैसला महीने भर पहले ही हो गया था. पर हो सकता है कि मजदूरों का प्रदर्शन उसके लिए तात्कालिक कारण बन गया हो. इसके बावजूद उनके इस्तीफे पर कलकत्ता के व्यापारियों को आश्चर्य हुआ और यह चर्चा जोर पकड़ने लगी कि मैक्नेइल ऐंड मैगोर पर आधिपत्य समेत इंजीनियरिंग, चाय और व्यापारिक क्षेत्र में 600 करोड़ रुपए का साम्राज्य संभालने वाले खेतान परिवार ने आखिरकार घाटा खा रहे मेटल बॉक्स से अपना रिश्ता तोड़ने का फैसला कर लिया. बिड़ला समूह के एक बड़े अधिकारी कहते हैं, "ऐसी खस्ताहाल कंपनी के साथ अपना नाम कौन जुड़ा रहने देना चाहेगा? वैसे ब्रिटेन वाले शेयरों के बल पर कंपनी अब भी उनके हाथ में है. परदे के पीछे से वे ही सारा काम चलाएंगे."

मेटल बॉक्स कर्मचारी संघ के एक नेता ने भी कहा कि खेतान अकुशल प्रबंधक थे और बाजार की तीव्र प्रतिद्वंद्विता देखकर उन्होंने हाथ ऊपर कर दिए.

लेकिन ये नतीजे उतने सच भी नहीं हैं. पहले निष्कर्ष में तो कुछ दम है. 136 करोड़ के कारोबार वाली कंपनी को चलाने में खेतान परिवार प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होगा लेकिन वे कंपनी से पूरी तरह बाहर नहीं निकले हैं. उनकी जगह प्रबंधक मंडल में उनके द्वारा मनोनीत दो लोग आ गए हैं. खेतान परिवार ने मेटल बॉक्स के अपने 7.6 फीसदी शेयर भी नहीं बेचे हैं.

अपने दफ्तर में दीपक : मैदान से हटे

भवान सिंह

"कंपनी के पुनर्जीवन का मामला श्रमिक समझौते पर ही निर्भर है और मामला वहीं अटका है. कंपनी की हालत खराब होती गई और हमें लगा कि अब हम कुछ नहीं कर सकते"

दीपक खेतान

वैसे उन्हें अच्छी कीमत मिले तो वे ये शेयर बेच भी सकते हैं. वे मेटल बॉक्स के झमेले से ऊब गए हैं. बॉल बियरिंग का उत्पादन शुरू करने के अदूरदर्शी फैसले से इस कंपनी की समस्याओं की शुरुआत हुई. फिर ज्यादा कुशल कंपनियों से प्रतिद्वंद्विता, देनदारियों का बोझ और ऊंची लागत के कारण हालत खराब होने लगी. उबरने के लिए कंपनी ने अपनी जायदाद तक बेचकर रकम जुटाने की कोशिश की.

प्रबंधकों ने वेतन कम करने, वेतन भुगतान स्थगित रखने और 7200 मजदूरों में से 30 फीसदी से ज्यादा की छंटनी करने का प्रस्ताव रखा है. 136 करोड़ की बिक्री वाले कारोबार में करीब 26 फीसदी तो वेतन में ही चले जाते हैं. यह 55 साल पुरानी कंपनी वेतन के मामले में 'स्वर्ग' मानी जाती है. लेकिन कर्मचारी संगठनों ने इन कदमों का विरोध किया. कुछ महीने पहले नाराज कर्मचारियों से पाला पड़ने पर बी.एम. खेतान ने कंपनी को ही छोड़ने का प्रस्ताव रख दिया.

वैसे कंपनी की श्रमिक समस्या दूर करने की कोशिश के संकेत दिख रहे हैं. पिछले पखवाड़े के आखिर में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु प्रबंधकों और इंटक नियंत्रित मजदूर संघ के साथ बैठक करने वाले थे. अगर कोई समझौता हो गया तो चार महीने से बंद पड़ी नौ इकाइयां फिर काम शुरू कर सकेंगी.

दीपक कहते हैं, "कंपनी के पुनर्जीवन का मामला श्रमिक समझौते पर ही निर्भर है और मामला वहीं अटका है. बैंक इसी के निबटारे की बाट जोह रहे हैं. इसी बीच कंपनी की हालत खराब होती गई है. हमें लगा कि अब हम कुछ नहीं कर सकते."

ऐसे में कंपनी का भविष्य धूमिल ही दिखता है. पर कंपनी के उपप्रबंध निदेशक आर.एस. झावर उत्साहित लगते हैं, "हम कंपनी को फिर ठीक तरह से चलाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे." लेकिन मामला अब प्रबंधकों के हाथ में नहीं रह गया है. फिलहाल तो कंपनी की चाबी औद्योगिक वित्त और पुनर्रचना बोर्ड के हाथ में है.

—**पलकुन्नथु जी. मथाई,** कलकत्ता में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शेयर बाजार

सुधार के लक्षण

प्रमुख शेयरों की कीमत चढ़ी

आखिरकार बाजार का माहौल बदला. वित्तीय वर्ष खत्म होते समय (संपत्तिकर के बोझ को कम करने के लिए) शेयर निकालने का दबाव खत्म होते हुए रबी की फसल मंडियों में पहुंचते ही बाजार में जान लौट आई. वैसे इकॉनामिक टाइम्स शेयर मूल्य सूचकांक में बहुत बढ़ोतरी नहीं हुई. यह मार्च में आए वर्ष के न्यूनतम स्तर 218 से चढ़कर 22 अप्रैल को 223.4 प्वाइंट तक ही पहुंचा लेकिन कुछ प्रमुख शेयरों की कीमत बहुत बढ़ी.

जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर 77 रुपए से उठकर 108.50 रुपए पर आ गए. उसकी कीमत में अगर 40 फीसदी से ज्यादा वृद्धि हुई तो दूसरी प्रमुख पोलिएस्टर कंपनी, ओरके के शेयर भी 35.2 फीसदी चढ़े. गरवारे नायलॉन, इंडियन आर्गेनिक केमिकल्स और वडोदा रेयंस के शेयरों की कीमत भी बढ़ी.

चार्ट: बी.के. शर्मा

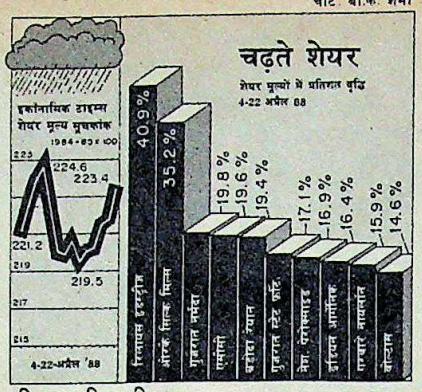

इंजीनियरिंग उद्योग (एटलस कोपको), सीमेंट (एसीसी), रासायनिक खाद उद्योग (गुजरात फर्टिलाइजर और गुजरात नर्मदा) और टाटा समूह की दोनों प्रमुख कंपनियों (टिस्को और टेल्को) के शेयरों में भी सुधार हुआ. पर लगता है कि निवेशकों को अब याद आया है कि बजट में सीमेंट उद्योग को भी रियायत दी गई थी. मानसून अच्छा होने तथा खरीफ के लिए भारी-भरकम सरकारी योजना से रासायनिक खाद उद्योग में माल का भंडार जमा होने की जोखिम भी उन्हें अब नहीं दिखती. सीमेंट कंपनियां तो अब मुनाफे के मामले में बेहतर स्थिति में हैं.

ऐसे माहौल में घाटे में रहने वाले शेयरों की संख्या कम ही है. इनमें विम्को (खराब वार्षिक परिणाम), काइनेटिक इंजीनियरिंग, मोटर इंडस्ट्रीज और अशोक लेलैंड जैसी वाहन उद्योग की कंपनियां शामिल हैं.

बाजार की स्थिति सुधरने में यूनिट ट्रस्ट की खरीद और छोटी बिक्रियों के लिए निर्धारित की गई कड़ी वित्तीय सीमाओं का भी बड़ा हाथ है. जीवन बीमा निगम ने भी कुछ चुने हुए शेयर उठाए. यह उम्मीद भी की जा रही थी कि बजट पर बहस समाप्त करते हुए सरकार कई रियायतों की घोषणा करेगी जिनमें लाभांश पर आयकर और कंपनी मुनाफे पर न्यूनतम 30 फीसदी कर को समाप्त करने का कदम भी होगा.

अगर अभी का माहौल बना रहता है तो खरीद-फरोख्त की मौजूदा पाबंदियां उठा लेनी चाहिए. इस बीच टिस्को ने रिकार्ड उत्पादन, सेंचुरी ने कारोबार में 36 फीसदी बढ़ोतरी और रिलायंस ने अपने 15 महीने के बढ़े हुए वित्त वर्ष के कारण अंतरिम लाभांश देने की घोषणा की है. ऐसे में बाजार का भविष्य निश्चित ही अच्छा रहना चाहिए.

जमा स्टॉक

	1988 ऊंचा	1988 नीचा	1988 बंद 22.4.88	पखवाड़े में स्टॉक की स्थिति
अशोक लेलैंड	36.50	30.25	33.50	0.50 −
एसोसिएटेड सीमेंट	180.00	129.00	158.50	29.50 +
एटलस कोप्को	63.50	33.50	40.00	3.00 +
एशियन पेंट्स	169.00	128.75	137.50	2.50 +
बजाज ऑटो	520.00	187.50	197.50	1.25 +
बड़ौदा रेयॅन	220.00	140.00	215.00	40.00 +
बाटा इंडिया	71.50	50.50	60.75	2.00 +
बेयर	335.00	280.00	335.00	5.00 +
भारत फोर्ज	126.50	101.00	114.00	1.00 −
बिरला जूट	44.00	32.25	37.70	0.20 +
ब्लो प्लास्ट	125.00	28.00	36.00	4.50 +
बॉम्बे डाइंग	138.00	94.00	118.00	3.00 −
ब्रिटानिया इंडिया	109.00	75.00	78.00	3.50 +
ब्रुक बांड	88.25	75.00	88.00	3.50 +
सीएट टायर्स	88.00	62.50	65.00	5.75 −
सेंचुरी एंका	837.00	617.50	787.50	12.50 +
क्लोराइड इंडिया	80.50	59.00	62.00	1.00 +
कोलगेट	220.00	160.00	165.00	1.50 −
सायनामिड	49.00	33.00	39.50	7.00 −
डीसीएम	38.25	28.00	32.00	2.50 +
डनलप	83.00	71.00	74.50	0.50 −
इंडियन होटल्स	48.00	38.00	47.00	1.00 +
एस्कार्ट्स	44.00	37.00	39.50	0.25 +
फिनोलेक्स केबिल्स	380.00	272.50	282.50	7.50 −
फूड स्पेशिलिटीज	142.00	93.50	101.50	3.00 −
गरवारे नाइलोन	37.00	20.00	36.50	3.50 +
जी.ई. शिपिंग	28.25	20.50	27.75	0.40 +
गुजरात स्टेट फर्टि.	118.00	75.00	92.50	11.00 +
ग्रासिम इंडिया	104.75	81.50	88.50	4.50 +
हिंदु. एल्यूमिनियम	139.00	73.00	73.00	4.00 −
हिंदुस्तान कोकोआ	215.00	67.50	71.00	2.75 −
हिंदुस्तान लीवर	81.00	59.50	65.00	—
हिंदुस्तान मोटर्स	25.00	15.80	16.80	0.40 +
हिंदुस्तान डॉर	212.50	102.50	107.50	22.50 −
आई.ई.एल.	43.75	31.00	33.00	0.25 −
इंडियन आर्गेनिक	23.00	15.00	19.50	3.00 +
इंडियन रेयॅन	60.00	46.00	57.50	1.25 −
इंड्राल	223.75	133.75	140.00	1.25 −
इंगरसॉल-रैंड	335.00	210.00	212.50	20.00 −
आई.टी.सी.	39.75	30.00	33.00	0.75 −
जे.के. सिंथेटिक्स	69.00	45.50	49.50	0.75 +
काइनेटिक इंजी.	200.00	161.25	175.00	7.50 −
किर्लोस्कर क्युमिंस	57.50	48.00	55.00	1.00 +
केएसबी पम्प	425.00	215.00	237.50	7.50 −
लारसन-टुब्रो	95.50	75.50	82.00	4.50 +
लिप्टन	67.00	52.00	60.00	1.50 +
लोहिया-मशीन्स	13.50	9.00	11.00	1.00 +
मदुरै कोट्स	77.00	59.00	71.00	1.00 −
महिंद्रा-महिंद्रा	63.00	48.50	52.00	2.00 +
मोटर इंडस्ट्रीज	587.50	447.50	475.00	7.50 −
मुकुंद आयरन	87.50	72.50	87.00	6.00 +
नेशनल आर्गेनिक	525.00	390.00	450.00	7.50 +
निरलॉन	8.75	5.00	7.25	1.25 +
ओरके सिल्क मिल्स	30.00	17.00	24.00	5.25 +
ओटिस एलिवेटर	215.00	161.25	166.25	18.75 −
पेइको इलेक्ट्रॉनिक्स	33.75	24.50	27.75	0.75 +
फाईजर	79.50	50.00	55.00	1.00 +
प्रीमियर ऑटो	31.00	23.00	26.25	1.75 +
रैनबेक्सी	102.50	76.00	84.00	2.00 +
रेमंड	96.00	41.50	43.25	1.25 −
रॉकिट ऐंड कोलमैन	214.00	175.00	184.00	7.00 −
रिलायंस इंडस्ट्रीज	117.00	69.00	108.50	26.50 +
शॉ वैलेस	132.00	50.50	53.50	—
सीमेन्स इंडिया	80.00	56.00	59.00	1.00 −
श्रीराम फाइबर्स	42.75	32.50	38.50	1.12 −
एसकेएफ बैयरिंग	1365.00	1058.00	1215.00	5.00 −
स्पिक	37.00	23.50	29.60	2.35 +
टाटा स्टील	696.25	568.75	695.00	27.50 +
टेल्को	472.50	340.00	460.00	2.50 +
विम्को	24.00	11.00	12.00	1.50 −

भारतीय रुपए का मूल्य

देश	मुद्रा	इकाई	बिक्री मूल्य (रुपए में)	क्रय मूल्य (रुपए में)
आस्ट्रेलिया	डालर	1	9.8984	9.8910
आस्ट्रिया	शिलिंग	1	1.1355	1.1232
बहरीन	दीनार	1	34.9732	34.9083
बांग्लादेश	टका	100	41.7910	41.7032
कनाडा	डालर	1	10.7846	10.6728
डेनमार्क	क्रोनर	1	2.0748	2.0531
मिस्र	पौंड	1	9.3610	9.3018
फ्रांस	फ्रैंक	1	2.3809	2.3201
हांगकांग	डालर	1	1.7027	1.6853
इंडोनेशिया	रुपिया	100	0.0078	0.0073
ईरान	रियाल	100	19.6432	19.5817
इटली	लीरा	100	1.0632	1.0328
जापान	येन	100	10.80	10.55
केन्या	शिलिंग	1	0.7532	0.7136
कुवैत	दीनार	1	48.4481	48.3713
मलेशिया	डालर	1	5.1771	5.1215
मारीशस	रुपया	1	1.0432	1.0000
नेपाल	रुपया	1	0.6160	0.5732
हालैंड	गिल्डर	1	7.1109	7.0363
पाकिस्तान	रुपया	1	0.7310	0.7009
सिंगापुर	डालर	1	6.6504	6.5775
स्पेन	पेसो	1	0.1180	0.0983
श्रीलंका	रुपया	1	0.4232	0.3998
स्वीडन	क्रोनर	1	2.2724	2.3574
स्विट्जरलैंड	स्विस फ्रैंक	1	9.6498	9.5467
तंजानिया	शिलिंग	1	0.1532	0.1490
थाईलैंड	बहत्त	100	52.2330	51.1992
ब्रिटेन	पौंड	1	25.0775	24.9400
सं. राज्य अमेरिका	डालर	1	13.2975	13.1650
सं. अरब अमीरात	दिरहाम	1	3.5932	3.5430
सोवियत संघ	रूबल	1	22.1932	22.8186
पश्चिम जर्मनी	जर्मन मार्क	1	0.0908	7.8864

स्रोत—बैंक ऑफ टोक्यो, नई दिल्ली, 22.4.88

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सोवियत संघ के उत्सव भारत 1987-88

सोवियत संघ

सचित्र मासिक पत्रिका

नये जीवन का निर्झर

विश्व की बीस भाषाओं में प्रकाशित यह पत्रिका अपने पाठकों को सोवियत जीवन के सभी पहलुओं से, सोवियत जनता की रोज़मर्रा की ज़िन्दगी और काम से परिचित कराती है ।

सोवियत पुरुषों और महिलाओं के जीवन के सभी पहलुओं तथा क्रियाकलापों में नये खुलेपन के वातावरण को प्रतिबिम्बित करती है ।

एक वर्ष २५ रुपये
तीन वर्ष ५० रुपये

सोवियत संघ

साथ में २५/५० रुपये डिमांड ड्राफ्ट/मनी आर्डर रसीद संलग्न है

नाम _____

पता _____

_____

यह विज्ञापन और भुगतान निम्न पते पर भेजिये

मैगज़ीन सेन्टर
एम.सी.डी. बिल्डिंग
नं. २, दूसरी मंज़िल
देशबन्धु गुप्ता रोड, पहाड़गंज
नई दिल्ली-११००५५

राजस्थान पीपल्स पब्लिशिंग हाऊस (प्रा.) लि.
चमेलीवाला मार्किट,
एम.आई.रोड, जयपुर-३०२००१

विंश शताब्दि
७५-सि, पार्क स्ट्रिट
कलकत्ता-७०००१६

नवचेतन बुक्स (प्रा.) लि.
५-ई रानी झांसी रोड
नई दिल्ली-११००५५

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अनाज

उपज बढ़ने पर भी टोटा

रबी ने तो साथ दिया पर खरीफ का कोई भरोसा ही नहीं

मंजीत सिंह पिछली रात को नहीं सोया. लेकिन वह थका नहीं था. पूरी रात वह एक थ्रेशिंग मशीन की बगल में खड़ा रहा और मशीन द्वारा गेहूं के डंठलों का लीला जाना देखता रहा. मशीन के मुंह के नीचे रखी एक बड़ी बाल्टी में गेहूं गिरता जा रहा था. सुबह तक उसके ट्रैक्टर की ट्रॉली गेहूं से भर गई थी. इस बार धरती ने सोना उगला था.

सूरज की तीखी किरणों की जरा भी परवाह न कर वह अपने ट्रैक्टर को लहलहाते गेहूं के खेतों की बगल से भगाते हुए पास की हापुड़ मंडी (गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश) जा रहा था. रास्ते में सोचता जा रहा था कि अनाज को बेचने के बाद वह क्या-क्या काम करेगा. उसकी खरीफ की फसल नष्ट हो गई थी और वह कर्जदार हो गया था. लिहाजा, गेहूं बेचने के बाद वह इस कर्ज का एक हिस्सा चुकाएगा, अपनी पत्नी प्रकाश कौर के लिए सलवार-कमीज खरीदेगा, सात साल के बेटे बिक्रमजीत के लिए एक फुटबाल और छह माह के परमजीत के लिए झुनझुना भी. लेकिन वह ज्यादा खर्च नहीं करना चाहता. सोचता है, "मुझे पैसे बचाकर रखने चाहिए. अगर कहीं खरीफ की फसल फिर दगा दे गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा."

और ऐसे ही विचार दिल्ली के कृषि भवन में बैठे कृषि अधिकारियों के दिमाग में उस समय दौड़ने लगे जब उन्होंने राज्यों से आई रबी फसल की खबरों की पिछले हफ्ते समीक्षा की. ताजा अनुमान है कि इस बार 6.6 करोड़ टन अनाज पैदा होगा जो कि एक रिकार्ड होगा. रबी की मुख्य फसल गेहूं की पैदावार 4.7 करोड़ टन तक पहुंच जाने की संभावना है. विनाशकारी सूखे की मार सहने के बाद भारत की कृषि के लिए इससे अच्छी कोई खबर नहीं हो सकती.

लेकिन उनकी खुशी एक गंभीर विचार से काफूर हो गई. देश के अनाज भंडार भरे नहीं. देश की कृषि सुरक्षा का बैरोमीटर माने जाने वाले भारतीय खाद्य निगम (भाखानि) के भंडारों में पिछले हफ्ते 2.3 करोड़ टन से घटकर 1.1 करोड़ टन अनाज रह गया. भाखानि के अध्यक्ष टी.एस. ब्रोका कहते हैं, "रबी की फसल से हमारे भंडारों में अनाज तो आएगा ही लेकिन हमें उससे कहीं ज्यादा अनाज सुरक्षित रखने की जरूरत है ताकि खरीफ के मौसम के दौरान आने वाली किसी भी विपत्ति से निबटा जा सके."

सरकार ने दो साल में पहली बार 10 लाख टन गेहूं आयात करने की योजना बनाई है. केंद्रीय खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव डॉ. डी.एन. प्रसाद जोर देकर कहते हैं, "जब भी जरूरत पड़ेगी हम अधिक आयात करेंगे."

सरकार ने इस बार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 173 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है ताकि किसान उसे ज्यादा गेहूं बेच सकें. यह पिछले साल से सात रुपए ज्यादा है. लिहाजा इस बार केंद्रीय और राज्य एजेंसियां एक करोड़ टन या कुल गेहूं उत्पादन का लगभग पांचवा भाग उगाहेंगी.

पिछले साल के सूखे के कारण ही आज देश के सामने कई तरह की समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं. खरीफ की फसल, जो आम तौर पर देश के कुल अनाज उत्पादन का लगभग दो-तिहाई होती है, सिर्फ 7.2 करोड़ टन ही हुई (चार्ट देखें). फिर भी रबी की अच्छी फसल से अनाज का उत्पादन 13 करोड़ टन से ज्यादा होने की संभावना है. और जैसा कि एक अधिकारी कहते हैं, "इससे कम-से-कम हम छह महीने तक चैन की सांस ले सकेंगे."

चिंता का दूसरा क्षेत्र है देश में तिलहनों का कम उत्पादन. तिलहनों का कुल उत्पादन सामान्य उत्पादन से 20 लाख टन कम होने की संभावना है. नवंबर से केंद्र ने 440 करोड़ रुपए की लागत से 8.7 लाख टन तेल आयात किया है. अब नागरिक आपूर्ति विभाग में संयुक्त सचिव एस.वी.एम. त्रिपाठी कहते हैं,

करनाल मंडी में गेहूं की आमद

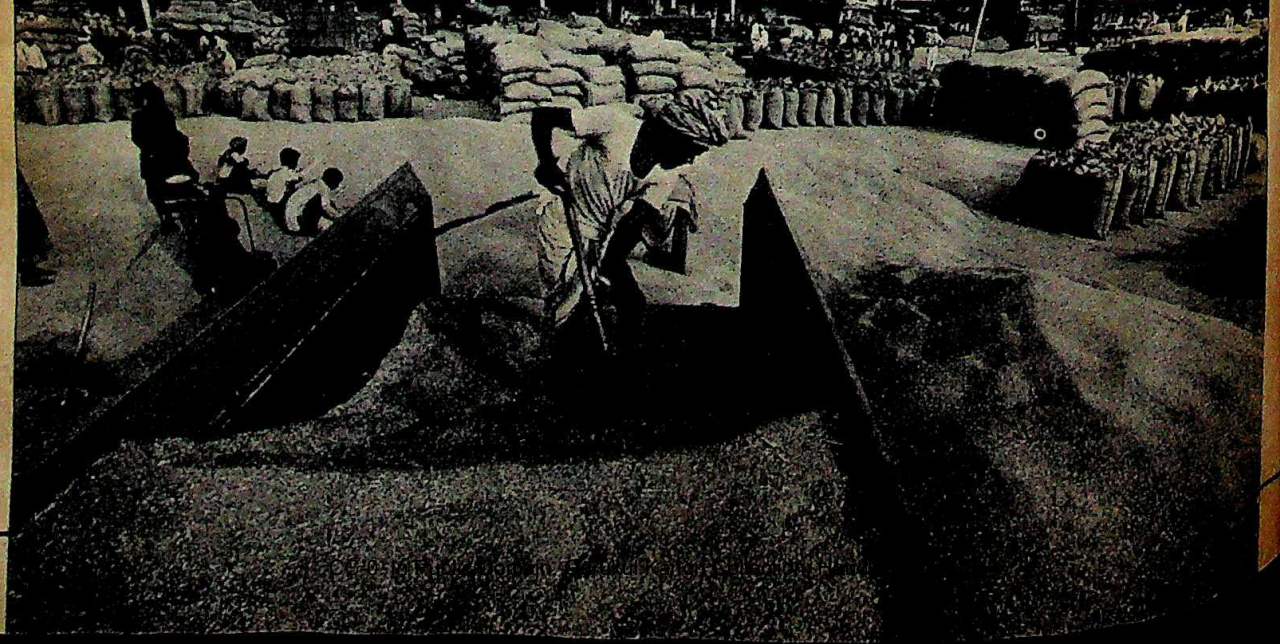

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रबी की फसल से हालत कुछ सुधरी है. हम कीमतों पर नजर रखेंगे और अगर जरूरत हुई तो और आयात करेंगे."

लेकिन उत्साहवर्द्धक बात यह है कि उत्तर भारत में जाड़े में बहुत कम वर्षा के बावजूद उम्मीद से भी अच्छी रबी की फसल हुई. संयोग तो यह है कि दक्षिण में इस दशक का सबसे अच्छा उत्तरी-पूर्वी मानसून रहा जिससे चावल और तिलहनों की शानदार फसल हुई. फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक प्रताप नारायण कहते हैं, "बहुत अच्छी फसल हुई और इससे पता चलता है कि हमारी कृषि में निश्चित तौर पर नई शक्ति का संचार हो सकता है."

हरेक की निगाहें अब इस साल की खरीफ फसल पर लगी हुई हैं. मौसम विभाग 'एल निनो' से संबंधित रिपोर्टों पर लगातार नजर रखे हुए है. 'एल निनो' उस घटना को कहते हैं जिसके कारण पैरुवियाई किनारे से दूर समुद्र यदा-कदा असामान्य रूप से गरम हो जाता है. पिछले साल के सूखे का यह मुख्य कारण था. खुशी की बात है कि समुद्र का तापमान, जो 'एल निनो' साल के दौरान चार डिग्री से भी ज्यादा बढ़ जाता है, तेजी से घटकर सामान्य हो गया. इससे इस साल भारत में अच्छी बारिश हो सकती है.

लेकिन सरकारी अधिकारी किसी तरह का खतरा मोल नहीं ले रहे हैं. पिछले महीने कृषि भवन ने कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए अपनी अति-महत्वाकांक्षी योजना पर अमल करना शुरू कर दिया. उसका इरादा अगले साल तक 16.6 करोड़ टन कृषि उत्पादन का है ताकि 15.2 करोड़ टन का पिछला रिकार्ड टूट जाए. और 1990 तक उसका इरादा तो 17.5 करोड़ टन अनाज पैदा करने का है.

जिस सरकार ने कभी दावा किया था कि वह तेजी से काम करेगी, वह अब सही में चलने लगी है. तीन महीने के भीतर ही योजना आयोग (कृषि) के सदस्य डॉ. के.ई. अलघ की अध्यक्षता वाले एक कार्य-दल ने भारत की 'दूसरी हरित क्रांति' की रूपरेखा पेश कर दी. इसमें 14 राज्यों में 169 जिले चुने गए. ज्यादातर जिले सिंचित क्षेत्रों में हैं. यहां कृषि उत्पादन बढ़ाने वाली सभी जरूरी चीजें मुहैया कराई जाएंगी. इस पर 150 करोड़ रु. की लागत आएगी.

विभिन्न राज्यों के कृषि विभागों ने इस कार्य योजना पर अमल करना भी शुरू कर दिया है. चुने हुए हर जिले में 100 खुदरा दुकानें खोली जा रही हैं जिन्हें बुआई के तीन महीने पहले ही खाद से भर दिया जाएगा. छोटे किसानों की सुविधा के लिए खाद कंपनियां 50 किलो के बदले 10 से 25 किलो के पैकेट सप्लाई करेंगी. वितरण केंद्रों को भी उम्दा बीजों से भरा जा रहा है.

कार्यदल की सिफारिशों के आधार पर ही केंद्रीय बजट में खाद की कीमतों में साढ़े सात फीसदी छूट की घोषणा की गई थी. उत्पाद शुल्क घटा दिया गया और कीटनाशक रसायनों को उत्पाद शुल्क से बिल्कुल मुक्त कर दिया गया. इससे इन रसायनों की कीमतें घटकर आधी हो गईं. फसल के लिए दिए जाने वाले कर्जों पर ब्याज की दर भी डेढ़ से ढाई फीसदी तक घटा दी गई.

मानो इतना ही पर्याप्त नहीं था. चुनिंदा जिलों को और रियायतें दी गईं. इनमें से एक-तिहाई जिलों में किसानों को कर्ज मिलने के रास्ते बंद हो गए थे. कार्य योजना के तहत उनके बकायों की भरपाई और कर्ज के रास्ते फिर से खोलने के लिए कुल 33 करोड़ रु. की रकम कर्ज के बतौर दी गई. इस बीच सिंचाई व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 12 लाख नलकूप भी खोदे जा रहे हैं.

लेकिन जितनी तेजी से राज्य सरकारों पर यह योजना थोपी गई, उसके अनुरूप अपने को ढालने के लिए वे अभी कोशिश ही कर रही हैं. बिहार के कृषि विकास आयुक्त पी.एस. कोहली कहते हैं, "हमारे सामने कठिन काम है. लेकिन इसे पूरा करने की जरूरत है." ऐसी भी सुगबुगाहट है कि कार्य योजना में अदूरदर्शिता दिखाई गई है. मसलन, इसमें सूखे और वर्षा के भरोसे रहने वाले इलाकों की उपेक्षा की गई है. लेकिन डॉ. अलघ इस कथन को 'बकवास' बताते हुए कहते हैं कि चालू विकास परियोजनाओं की धनराशि में किसी भी तरह की कटौती नहीं की जा रही.

फिर भी, सरकार की बनाई बेहतरीन योजनाएं अभी भी आम तौर पर मानसून पर ही निर्भर करती हैं. खरीफ की मुख्य फसल धान है और इसका 60 फीसदी वर्षा पर आधारित जमीन पर ही उगाया जाता है. चुनिंदा जिले भले ही खराब मानसून की मार से बच जाएं, भारतीय कृषि नहीं बच सकती.

—राज चेंगप्पा

चार्ट: बी.के. शर्मा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पाकिस्तानी सीरियल

मनोरंजन के मोर्चे पर आगे

पड़ोसी मुल्क के कार्यक्रमों के कैसेट अब हर कहीं सुलभ

लगता है कि दूरदर्शन का सीरियल-तिलिस्म अब टूट रहा है. वे दिन हवा हुए जब 'हम लोग', 'बुनियाद' या 'नुक्कड़' जैसे सीरियल शहरों-कस्बों में कर्फ्यू जैसी हालत पैदा करने की हैसियत रखते थे. अब सिवाय रविवार की सुबह प्रसारित होने वाले 'रामायण' के एक भी ऐसा सीरियल नहीं बचा है जो भारतीय दर्शकों को 'ईडियट-बॉक्स' से बांधे रख पाने की हैसियत रखता हो. उधर हिंदी फिल्मों की उबाऊ एकरसता भी हिंदी वीडियो प्रेमियों की बरदाश्त की सीमाओं पर दस्तक देने लगी है.

ऐसे में हैरानी की बात नहीं कि दिल्ली, करनाल, लखनऊ और ऐसे ही बीसियों शहरों-कस्बों में वीडियो दर्शक पाकिस्तानी नाटकों और सीरियलों की ओर मुखातिब हो जाएं और वीडियो लाइब्रेरियों की शेल्फें पाकिस्तानी वीडियो कैसेटों से पट जाएं और टीवी-वीडियोधारी मध्यम वर्ग को अपनी लपेट में ले लें. उत्तरी दिल्ली में किराए की वीडियो लाइब्रेरी चलाने वाले मोहन दास (48) के शब्दों में, "पिछले छह महीने में हिंदी फिल्मों का हमारा धंधा बस आधा ही रह गया है. अब पाकिस्तानी कैसेटों की मांग इतनी अधिक रहती है कि कभी-कभी इसे पूरा कर पाना भी मुश्किल हो जाता है."

नई दिल्ली के पालिका बाजार में पाकिस्तानी कैसेटों का थोक धंधा करने वाली एक दुकान में पिछले पखवाड़े 211 किस्म के पाकिस्तानी कैसेट उपलब्ध थे जिनमें से नाटकों और सीरियलों के कैसेटों की संख्या 146 थी. चौंकाने वाली एक बात यह भी है कि हास्यप्रधान नाटकों और सीरियलों के मुकाबले गंभीर नाटकों और सीरियलों की लोकप्रियता भी किसी मायने में कम नहीं है. यदि 'सोना-चांदी', 'अंधेरा उजाला', 'घर रामा', 'आलिफ नून', 'हैलो हैलो', 'पर्ची' और 'फिफ्टी-फिफ्टी' जैसे हास्यप्रधान सीरियलों के कैसेट धड़ल्ले से देखे जा रहे हैं तो दक्षिणी दिल्ली में एक वीडियो दुकानदार प्रकाश कुमार (28) के अनुसार, "धूप-किनारे, रात, वारिस, तनहाइयां और स्तून जैसे सीरियलों की लोकप्रियता भी इतनी बढ़ चुकी है कि लोग दूसरी और तीसरी बार देखने के लिए भी कैसेट किराए पर ले जाते हैं." मजेदार बात यह है कि दस साल पुराने 'अंकल उर्फी' जैसे ब्लैक-ऐंड-व्हाइट सीरियल भी लोकप्रियता की ऊंची पायदान पर मौजूद हैं.

इसलिए यह कोई हैरानी की बात नहीं रही कि कम-से-कम उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों-कस्बों में तो शीबा हसन उर्फ 'चांदी' (सोना-चांदी), जमील फखरी उर्फ 'पैंट संभालू पुलिस इंस्पेक्टर', सुलतान खोसट उर्फ 'दस जमात पास हवलदार' (अंधेरा उजाला), राहत काज़मी और सायरा काज़मी (धूप किनारे), इस्माइल तारा (फिफ्टी-फिफ्टी) और समीना पीरज़ादा तथा अफजाल (रात) जैसे पाकिस्तानी टीवी सितारे अब वैसे ही चर्चित और घरेलू नाम बनते चले जा रहे हैं जैसे किसी जमाने में आलोकनाथ, अनीता कंवर, सतीश शाह और पंकज कपूर हुआ करते थे.

आखिर ऐसा क्या है पाकिस्तानी सीरियलों में जो उन्हें भारतीय दर्शकों में इतना लोकप्रिय बना रहा है? दिल्ली के शालीमार बाग की वीणा साहनी (35) कहती है, "पाकिस्तानी नाटक हों या सीरियल कहानी, अभिनय और निर्देशन सभी मामलों में वे दूरदर्शन से कहीं आगे हैं. दूरदर्शन की कॉमेडी भी पाकिस्तानी सोना-चांदी, पर्ची, फिफ्टी-फिफ्टी और आलिफ-नून के मुकाबले कहीं टिक नहीं सकती." शायद यही कारण है कि दूसरे कई परिवारों की तरह साहनी परिवार भी शाम के समय दूरदर्शन के 'जिंदगी', 'होनी-अनहोनी' और 'कशमकश' जैसे उबाऊ सीरियल देखने के बजाय कोई पाकिस्तानी कैसेट देखना अधिक पसंद करने लगा है.

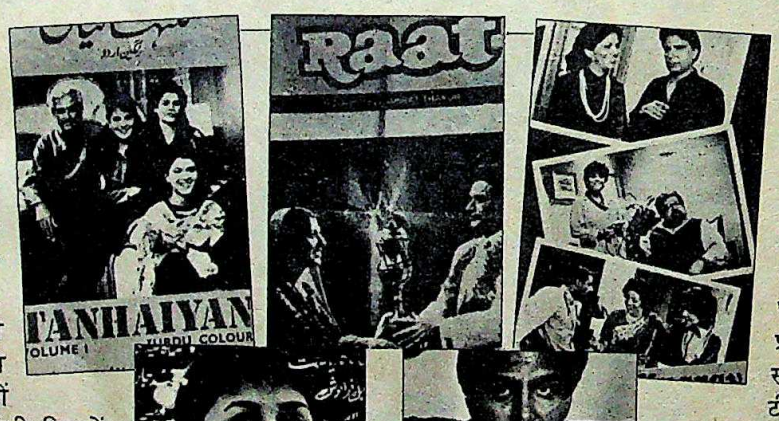

भारत में पाकिस्तानी प्रसारणों की इस लोकप्रियता पर किसी पाकिस्तानी की प्रतिक्रिया संतोषभरी होना स्वाभाविक ही है. रावलपिंडी टीवी के एक पुराने और चर्चित अभिनेता खालिद सैफुल इस्लाम आजकल नई दिल्ली के पाकिस्तानी दूतावास के प्रेस सूचना विभाग में अधिकारी हैं. उनका कहना था, "पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों की लोकप्रियता में मामला अभी तक इकतरफा बना हुआ था. यह खुशी की बात है कि पाकिस्तानी ड्रामा को भारत में लोकप्रियता हासिल हो रही है." अनौपचारिक बातचीत में दूतावास के मुलाज़िम स्वीकार करते हैं कि वे अपने परिवारों के लिए ताजा पाकिस्तानी वीडियो कैसेट लाहौर या रावलपिंडी से नहीं बल्कि पालिका बाजार से मंगवाया करते हैं.

नई दिल्ली की ही एक दुकान में 211 किस्म के पाकिस्तानी कैसेट उपलब्ध हैं जिनमें नाटकों और सीरियलों की संख्या 146 है

इन कैसेटों की लोकप्रियता की अपनी कहानी है. पाकिस्तान टीवी के इन कार्यक्रमों को पंजाब, जम्मू-कश्मीर और राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में बहुत साफ देखा जा सकता है. दुकान और उनका नाम प्रकाशित न करने की शर्त पर पालिका बाजार से इन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कैसेटों का थोक व्यापार चलाने वाले युवा व्यापारी पाली (कल्पित नाम) कहते हैं, ''1985-86 में 'तनहाइयां', 'वारिस' और 'अंधेरा-उजाला' की लोकप्रियता का अजीब आलम था. यह देखकर हमें लगा कि क्यों न इन सीरियलों के कैसेट तैयार करके उन इलाकों में भेजे जाएं जहां पाकिस्तानी टीवी प्रसारण नहीं देखे जा सकते.''

तीर ठीक निशाने पर लगा और आज हालत यह है कि दिल्ली, बंबई और अमृतसर में ऐसे डीलरों का एक सुनियोजित तंत्र बन चुका है जो अमृतसर में पाकिस्तानी नाटकों और सीरियलों की रिकॉर्डिंग करने, उनके कैसेट तैयार करने और डुप्लिकेटिंग करके शहरों-कस्बों के गली-मुहल्लों में चलने वाली वीडियो लाइब्रेरियों को सप्लाई करने के धंधे में लगा हुआ है. पाली के अनुसार, ''इस काम में फिल्मों के मुकाबले अधिक मुनाफा है. न रायल्टी का झगड़ा, न कैसेट के पिट जाने का जोखिम और न पाइरेसी के दावे करने वाले प्रोड्यूसर. सोने पर सुहागा यह कि भले ही सीरियल पांच साल पुराना हो, हिंदुस्तानी दर्शक के लिए तो वह एकदम ताजा और नया ही है.'' शायद यही कारण है कि दो घंटे की लंबाई वाला कैसेट 110 रुपए में बेचने के बाद भी कैसेट की कीमत और बाकी खर्चे निकालकर डीलर को कम-से-कम 20-25 गुना मुनाफा हो जाता है. आम तौर पर किसी भी अच्छे सीरियल की दो-ढाई हजार प्रतियां तो बिक ही जाती हैं.

पाकिस्तानी सीरियलों की इस उत्कृष्टता को दूरदर्शन के अधिकारी भी स्वीकार करते हैं. उनमें से एक के शब्दों में, ''व्यावसायिक नजरिये से उनके टीवी नाटक सचमुच शानदार हैं. करीने से लिखे गए करारे डायलॉग, एकदम स्वाभाविक अभिनय और उर्दू भी फारसी रंग वाली नहीं बल्कि पूरी तरह आधुनिक. सोने पर सुहागा यह कि उनकी अभिनेत्रियां बहुत सुंदर हैं.''

इस नए पाकिस्तानी सीरियल हमले का ही नतीजा था कि मंडी हाउस को अपनी अफसरशाही गिरफ्त में जकड़े बैठे अफसरों की एक विशेष बैठक इस बात पर विचार करने के लिए बुलानी पड़ी कि दूरदर्शन के नाटकों के तकनीकी और रचनात्मक पहलुओं में कैसे सुधार लाया जाए.

अतिरिक्त महानिदेशक शिव शर्मा के शब्दों में पाकिस्तानी नाटकों में न केवल जोरदार सेटों का इस्तेमाल होता है बल्कि वे एक साथ तीन-तीन कैमरों से शूटिंग करते हैं जो नाटक में एक खास गहराई पैदा करता है. हमारे यहां के अधिकांश सीरियल केवल एक कैमरे से फिल्माए जाते हैं.

लोकप्रियता के संदर्भ में पाकिस्तानी टीवी की अच्छे दर्जे की तकनीक, निर्देशन और कलाकारों के अभिनय के अलावा सीरियलों और नाटकों की भाषा और विषय के चुनाव की भी अच्छी-खासी भूमिका है. उदाहरण के लिए सोना-चांदी में शीबा की ठेठ पंजाबीदार उर्दू उस लंगड़ी हिंदी के बहुत नजदीक है जो भारतीय पंजाबियों के व्यक्तित्व से सीधी जुड़ी हुई है. इसी तरह घर रामा और फिफ्टी-फिफ्टी के चरित्रों की भाषा में लखनवी, भोपाली, हैदराबादी और दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में बोली जाने वाली उर्दू का पुट इतना गहरा है कि भारतीय दर्शक के लिए कई बार यही फर्क करना कठिन हो जाता है कि वह ऑल इंडिया रेडियो के चिर-परिचित चरित्रों को अपनी आंखों से देख रहा है या पाकिस्तानी चरित्रों को.

कहानियों का सामाजिक और सांस्कृतिक माहौल भी भारत से इतना गहरा मेल खाता है कि दर्शक पाकिस्तानी कहानी और चरित्रों में भारतीय समाज की झलक देखकर उससे नाता जोड़ लेने से बच नहीं सकता. उदाहरण के लिए 'अमावस' में तांगे वाले की बेटी मुसर्रत उत्तर भारत के ऐसे किसी भी गरीब परिवार में आसानी से फिट बैठ सकती है जिसमें दिन-ब-दिन जवान हो रही और कॉलेज जाने वाली बेटी के विवाह के लिए मां-बाप दहेज की चिंता में घुले जा रहे हैं. 'रात' में इम्तिहान में परचे बदलने और अध्यापकों को धमकियां देने के लिए पिस्तौलें लेकर सरेआम घूमने वाले लड़के भी उत्तर प्रदेश या बिहार के किसी कॉलेज से उठाए गए असली चरित्र लगते हैं. इसी तरह 'अंधेरा-उजाला' में डंडा फटकारकर हर किसी को धमकाने वाला पुलिस हवलदार सुलतान खूसट भी किसी हिंदुस्तानी थाने का ही पाकिस्तानी संस्करण दिखाई देता है.

'तनहाइयां' में डॉक्टर जोड़े की भूमिका में राहत काज़मी (बाएं) और मरीना खान

'पर्ची' में हर काम के लिए सिफारिशी पर्ची के महत्व का परिचय भी ठेठ भारतीय छवि पेश करता है. सिर्फ इतना ही नहीं, इस्माइल तारा और उसके पूरे खानदान (फिफ्टी-फिफ्टी) का बरसों पहले गुजर चुके अपने पिता की कब्र पर टेलीफोन लेकर हाजिर होना और उन्हें यह 'खुशखबरी' देना कि ''अब्बा हुजूर आपकी जवानी के दिनों में भेजी गई दरखास्त के जवाब में टेलीफोन डिपार्टमेंट ने कनेक्शन की मंजूरी भेज दी है'' हिंदुस्तानी दर्शक के मन को कहीं यह शांति भी प्रदान करता है कि भ्रष्टाचार और लालफीताशाही के मामले में उसका पड़ोसी देश भी बेहतर हालत में नहीं है. बल्कि जिस बेबाक अंदाज में 'अंधेरा-उजाला', 'पर्ची' और 'फिफ्टी-फिफ्टी' जैसे पाकिस्तानी सीरियल वहां की अफसरशाही और समाज के भ्रष्ट चरित्र को नंगा करके उसका सरेआम मजाक उड़ाते हैं उसे देखकर भारतीय दर्शक की वह इच्छा भी पूरी होने लगी है जिसकी उम्मीद वह दूरदर्शन से तो शायद हमेशा के लिए छोड़ चुका था.

—विजय क्रांति और रमिंदर सिंह

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सिर्फ़ प्यार ही नहीं चुका सकता इनकी दवाओं के बिल.

इसके लिए चाहिए मेडिक्लेम.

जी हां, मेडीक्लेम की हॉस्पिटलाइज़ेशन और डॉमिसिलियरी हॉस्पिटलाइज़ेशन बेनिफ़िट पॉलिसी आपके परिवार के लिए है एक अनोखा वरदान.

आपका ढेर सा प्यार...आपकी कंपनी की कोई भी मेडीकल योजना.... बड़ी-बड़ी बीमारियों, ऑपरेशन और दुर्घटना में इलाज पर होने वाले खर्च का बिल नहीं चुका सकती.

इसीलिए आपको चाहिए मेडीक्लेम. मेडीक्लेम के ज़रिए आप कई तरह के चिकित्सा लाभ हासिल कर सकते हैं– वह भी आपकी आवश्यकता, आपकी ज़रूरतों के अनुरूप.

यहां तक कि आप घर पर रहकर इलाज करने का खर्च भी पा सकते हैं.

साथ ही आप पारिवारिक-छूट और करों में छूट का लाभ भी उठा सकते हैं.

यदि आप अपने परिवार को सही मायने में प्यार करते हैं तो मेडीक्लेम योजना के अंतर्गत इनका बीमा कराइए.

जो आपको कम खर्च में दिलाए कहीं ज़्यादा सुरक्षा, कहीं ज़्यादा लाभ और यही है आपके प्यार का सच्चा सुबूत.

प्रीमियम प्रति वर्ष रु.	हॉस्पिटलाइज़ेशन रु.	डॉमिसिलियरी हॉस्पिटलाइज़ेशन रु.
२००	१०,५००	३,१००
२५०	१७,६००	–
३५०	२५,५००	–
६०० *	३७,७५०	५,२५०
८४० *	५२,७५०	७,४००
१,३०० *	८२,५००	११,५००

आयु सीमा ५ से ७० वर्ष

★ *अतिरिक्त प्रीमियम अदा करने पर व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी उपलब्ध.*

MEDICLAIM

मेडीक्लेम के प्रस्तुतकर्ता न्यू इंडिया एश्योरन्स

NEW INDIA ASSURANCE

A subsidiary of the General Insurance Corpn. of India

खतरे का कोई भी नाम.... बीमा करना हमारा काम.

CONTOUR ADS-NIA-27B&H HIN

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रदर्शन करते बंगाली खिलाड़ी: खेल का गिरता स्तर

संतोष ट्रॉफी

बेजान, विवादास्पद स्पर्धा

कर्नाटक-बिहार की 'करतूत' के खिलाफ पश्चिम बंगाल में शोर

हरदम दो-दो हाथ करने में मशगूल रहने वाले पश्चिम बंगाल के दो परंपरागत प्रतिद्वंद्वी इंका और सत्तारूढ़ वाममोर्चा पिछले पखवाड़े एक ही पाले में नजर आए. विधानसभा में वैसा ही तनावपूर्ण माहौल था जैसा कि अक्सर होता है. पर दोनों चिर-राजनैतिक शत्रु अपनी चिर-परिचित शैली में एक दूसरे पर राष्ट्र विरोधी होने की तोहमत नहीं मढ़ रहे थे. बजाय इसके, दोनों एक ही सुर में अपने साझा दुश्मनों—बिहार और कर्नाटक को कोस रहे थे.

प्रदेश के कांग्रेसी और वामपंथी दोनों मिलकर आसमान इसलिए सिर पर उठा रहे थे क्योंकि केरल के क्विलोन में हुई संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबाल चैंपियनशिप से बंगाल की टीम सेमी फाइनल से पहले ही बाहर हो गई थी या जैसा कि आरोप है—बाहर कर दी गई थी. बंगाल ने यह चैंपियनशिप 44 में से 22 बार जीती है और इस बार भी उसके समर्थक उसकी जीत की उम्मीद लगाए थे. बंगाल की टीम सेमी फाइनल तक भी नहीं पहुंच सकी.

सेमी फाइनल मुकाबलों के पहले तक बंगाल की टीम बेहतर हालत में थी और निश्चित भी. ग्रुप में दूसरे नंबर पर कर्नाटक की टीम थी और सेमी फाइनल में उसके पहुंचने का रास्ता तभी प्रशस्त हो सकता था जब वह बिहार की टीम पर कम-से-कम पांच गोल जड़ देती. ऐसा होने पर ही कर्नाटक का गोल औसत बंगाल से ज्यादा हो जाता. बिहार ने, खासकर उसकी रक्षापंक्ति ने समूचे टूर्नामेंट में बेहतर खेल दिखाया था. यहां तक कि बंगाल की टीम भी बिहार को सिर्फ एक गोल से ही हरा पाई थी और मैच देखने वाले कई लोगों का मानना है कि ऐसा भी तभी हो पाया जब मैच के आखिरी क्षणों में रेफरी बी.पी. कुटिन्हो ने बंगाल को उदारतापूर्वक एक पेनाल्टी किक का तोहफा दे दिया.

बंगाल को 'तोहफे' में मिले इस गोल ने अब तक की सबसे ऊबाऊ राष्ट्रीय प्रतियोगिता के आखिरी मौके पर सनसनी फैला दी. जैसे ही कर्नाटक-बिहार के बीच मैच शुरू हुआ, अपने पिछले तीन मैचों में एक भी गोल न करने वाली कर्नाटक की टीम अचानक ही बिहार के गोल पर हावी हो गई और इसके पहले हुए मुकाबलों में हरेक टीम को मुंहतोड़ जवाब देने वाले बिहार के मध्य और रक्षापंक्ति के खिलाड़ियों ने कर्नाटक के खिलाड़ियों को एक दूसरे को पास देने से भी रोकने की कोई कोशिश नहीं की.

जब पहले 18 मिनटों में ही कर्नाटक ने बिहार पर तीन गोल ठोक दिए तो साफ जाहिर हो गया कि मैच में क्या कुछ होने जा रहा है. मैच देख रहे बंगाल के खिलाड़ी थोड़ी देर तो भुनभुनाते रहे. फिर उन्होंने तय किया कि इस बारे में मैदान से बाहर कुछ किया जाए. यह मैच रुकवाने के लिए वे काले झंडे लेकर प्रदर्शन करने लगे. लेकिन केरल पुलिस ने उन पर लाठियां भांज दीं. घायल होने वालों में बंगाल और भारत के कप्तान सुदीप चटर्जी भी थे. सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे कटे पर नमक छिड़कना हो, बिहार के कप्तान शफीक ने मैच खत्म होने से पहले गेंद अपने ही गोल में डाल दी. इस तरह कर्नाटक की 6-0 से जीत हुई और बंगाल प्रतियोगिता से बाहर हो गया.

बंगाल टीम के मैनेजर मोंटू घोष बताते हैं, "हमारे लड़के इसलिए नाराज हुए क्योंकि हमें प्रतियोगिता से बाहर करने के लिए पहले से ही 'तय' मैच खेला गया."

लेकिन अधिकारी इस झमेले से परेशानी में पड़ गए. केरल फुटबाल संघ के अध्यक्ष टी.ओ. अब्दुल्ला ने कहा, "यह फुटबाल नहीं था. उन्होंने बंगाल से दुर्भावना के कारण खेल का सत्यानाश कर दिया." अब्दुल्ला इस 'साजिश' में केरल के शामिल होने के बंगाल के आरोप का खंडन करते हैं. उन्होंने भारतीय फुटबाल संघ को इस बखेड़े पर विचार करने के लिए आपातकालीन बैठक करने के लिए लिखा है. वे कहते हैं, "बंगाल का प्रतियोगिता में बने रहना हमें अच्छा लगता क्योंकि टिकटों की बिक्री बढ़ती."

यह दलील संकुचित तो है लेकिन एकदम सटीक भी. भारी प्रचार और शानदार इंतजामात के बावजूद फ्लडलाइटों वाला लालबहादुर शास्त्री स्टेडियम इस प्रतियोगिता में भीड़ आकर्षित नहीं कर पाया.

केरल के हताश अधिकारी इसका दोष भारतीय फुटबाल की खस्ताहालत को देते हैं. केरल के पूर्व खिलाड़ी आर. बालाकृष्णन ने कहा, "फुटबाल का स्तर गिरा है. लड़के बड़े ढीले-ढाले ढंग से खेलते हैं."

ये सब बातें केवल इसी दलील को पुख्ता करती हैं कि जब तक भारत के खिलाड़ियों को वैज्ञानिक तौर-तरीकों से, खास तौर पर विदेशी प्रशिक्षकों से प्रशिक्षण नहीं दिलाया जाता, तब तक देश में फुटबाल का भविष्य अंधकारमय ही बना रहेगा.

—श्रीधर पिल्लै

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आईआरएस-1ए

खजानों पर खोजी नजर

दूरसंवेदन उपग्रह स्थापित करने के साथ ही नए युग का सूत्रपात

अंतरिक्ष वैज्ञानिक उस समय खुशी से झूम उठे जब 17 मार्च को देश के ऊपर से उड़ान भरती हुई बाज की तरह की उस चीज ने अपनी पैनी आंखें दिल्ली, पुणे, कोल्हापुर और पणजी पर गड़ा दीं. पक्षी जैसी यह चीज और कुछ नहीं, उन्हीं के हाथों बना भारतीय दूरसंवेदी उपग्रह (आईआरएस-1ए) था. उपग्रह ने देश पर से गुजरते हुए तकरीबन एक हजार चित्र लिए जिनमें से कुछ तो अद्भुत क्लोज-अप थे. इसी के साथ भारत में दूरसंवेदन का एक नया युग आरंभ हो गया.

आईआरएस-1ए की अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक रवानगी का श्रेय बंगलूर के भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान (इसरो) को जाता है. भारत अब दूरसंवेदी उपग्रहों से धरती और सागर के शोधपूर्ण चित्र खींचने वाले अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस और जापान जैसे देशों की कोटि में जा पहुंचा है. लेकिन भारतीय दूरसंवेदी उपग्रह तकनीक के मामले में दूसरे देशों के उपग्रहों से भिन्न है. 'इसरो' के अध्यक्ष प्रो. यू.आर. राव कहते हैं, "आईआरएस-1ए किसी तुलना के लिए बनाया भी नहीं गया. इसका मकसद है हमारे प्राकृतिक स्रोतों का नक्शा खींचना और यह अच्छे चित्र भेज भी रहा है."

"आईआरएस-1ए प्राकृतिक स्रोतों के अच्छे चित्र भेज रहा है"
यू.आर. राव
अध्यक्ष, अंतरिक्ष शोध संस्थान

इसके लिए 'इसरो' को करीब सात साल तक मेहनत-मशक्कत करनी पड़ी. 'इसरो' के बंगलूर स्थित उपग्रह केंद्र (इसाक) में तैनात परियोजना निदेशक के. कस्तूरीरंगन कहते हैं, "उपग्रह बनाना एक चुनौतीपूर्ण काम था और 'इसरो' के हम 1400 लोगों ने मस्तिष्क और हाथों के तालमेल से इसे मुमकिन कर दिखाया."

आईआरएस-1ए को 904 किलोमीटर ऊंची कक्षा में स्थापित किया गया. उपग्रह बनाने वालों को इसे इस्तेमाल करने वाले बहुत से लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखना था. कुछ फसलों की बदलती स्थितियों के अध्ययन के लिए अपेक्षाकृत छोटे चक्र में इकट्ठा किए गए आंकड़े चाहते थे तो. कुछ लोगों की मांग थी कि खनिज संभावनाओं के बारे में उन्हें विस्तृत आंकड़े मुहैया कराए जाएं. इसलिए इस उपग्रह को ऐसी कक्षा में स्थापित किया गया जहां वह 22 दिन में एक चक्र पूरा करके ज्यादा से ज्यादा लोगों की जरूरतों को पूरा कर सके.

'इसरो' ने इसके लिए सारे महत्वपूर्ण खोजी उपकरण और कैमरे अमेरिका के फेयरचाइल्ड कार्पोरेशन से खरीदे. पर ये कैमरे बादलों की परत से जमीन का नजारा नहीं ले सकते थे. पौधों पर नमी का विस्तृत असर जांचने, भूमिगत जलस्रोतों की खोज और समुद्र तथा बर्फ की तस्वीरें लेने के लिए ज्यादा आधुनिक माइक्रोवेव संवेदकों की जरूरत थी. उपग्रह द्वारा भेजे गए आंकड़ों की छानबीन करने और ये आंकड़े उपभोक्ताओं को सप्लाई करने वाली हैदराबाद की राष्ट्रीय दूरसंवेदी एजेंसी के प्रो. बी.डी. दीक्षातलु कहते हैं, "उम्मीद है भारत 1990 के मध्य तक ऐसी तकनीक विकसित कर लेगा." इसके बावजूद आईआरएस-1ए की उच्च तकनीक में भारतीय योगदान कम नहीं हैं. विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तिरुअनंतपुरम के वैज्ञानिकों ने उच्च दाब व कक्षीय नियंत्रण व्यवस्था को विकसित किया है.

इस उपग्रह से भूमिगत स्रोतों के खोज का काम जल्दी होगा, भूमिगत जल व खनिज संपदा के स्रोतों के नक्शे खींचे जा सकेंगे तथा जंगलों के विस्तार, फलों की वृद्धि और पानी के बहाव के बदलते हालात का जायजा लिया जा सकेगा. राष्ट्रीय दूरसंवेदी एजेंसी ये आंकड़े अमेरिकी और फ्रेंच एजेंसियों के 'लैंडसेट' और 'स्पॉट' उपग्रहों के आंकड़ों से सस्ते में बेचेंगी. 'इसरो' के प्रमुख राव मानते हैं कि उपग्रह आंकड़ों का सबसे महत्वपूर्ण इस्तेमाल सूखे की हालात पर निगाह रखने में होगा. भूमिगत जलस्रोतों का पता लगाकर और जलनिकासी के रास्तों का विस्तृत अध्ययन करके सूखे से निबटने की योजनाबद्ध कार्रवाई की जा सकेगी. 'इसरो' के

बाबजी/ जनता स्टूडियो

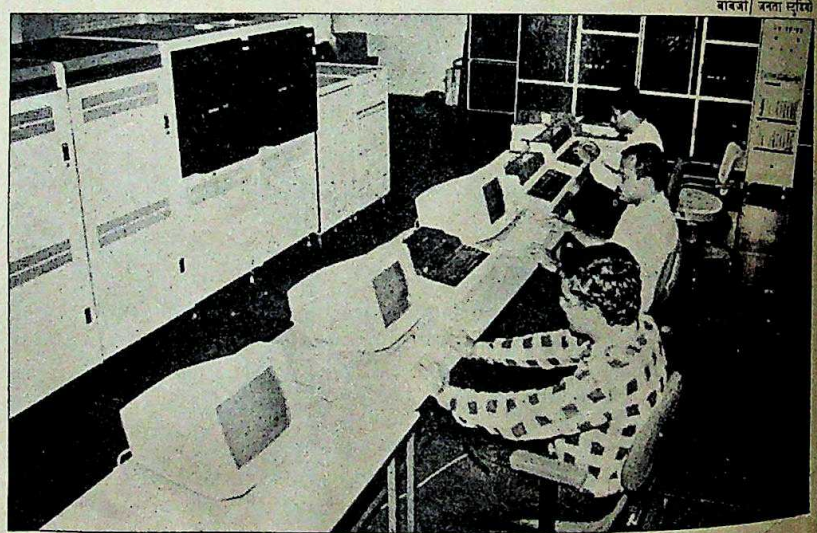

हैदराबाद के एनआरएसए में आंकड़ों का विश्लेषण

वैज्ञानिक सबसे पहले इस तरह के चार जिलों में परीक्षण के तौर पर अध्ययन करेंगे. ये जिले हैं—कोलार (कर्नाटक), भावनगर (गुजरात), ललितपुर (उत्तर प्रदेश) और पालघाट (केरल).

पर अंतरिक्ष में घूम रहे भारत के इस नए उपग्रह में सब कुछ ठीकठाक भी नहीं है. यह दिन में ही 'देख' सकता है जब सूरज जगमगा रहा हो. अब भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के सामने चुनौती ऐसे संवेदक विकसित करने की है जो दिन-रात तथा साफ और बादलों वाले मौसम में बराबर काम कर सके. तभी भारत दूरसंवेदी उपग्रह पर शोध करने वाले झंडाबरदारों की पांत में शामिल हो जाएगा. —अमरनाथ के. मेनन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जांबाज़, कामयाब मर्दों के लिए

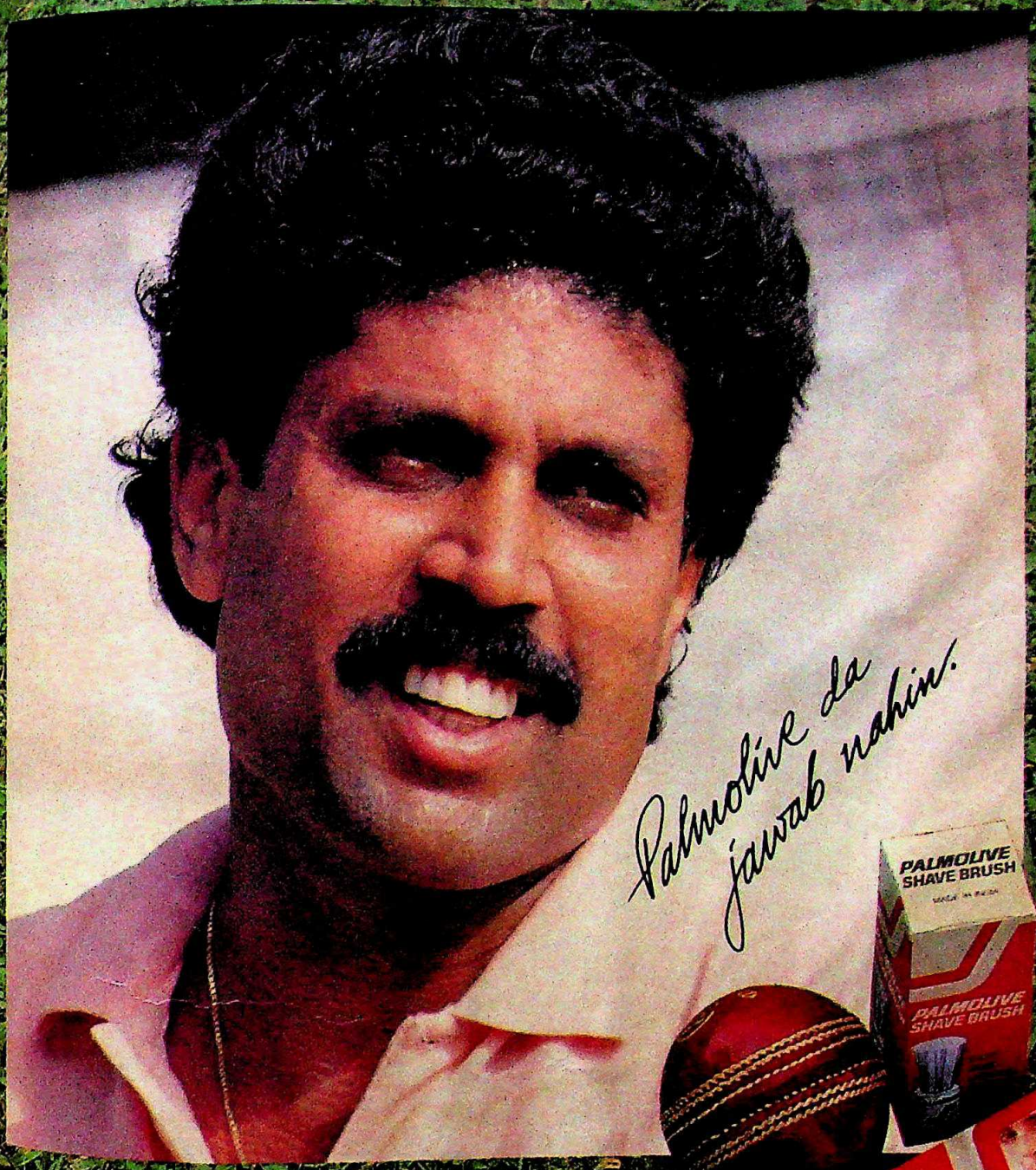

पामोलिव
शेव क्रीम और ब्रश

एस जी एल-4 युक्त

पामोलिव शेव क्रीम – डीलक्स लाथर, रेगुलर लेथर और मेंथॉल कूल में उपलब्ध.

Rediffusion/CP/5528 bHN

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

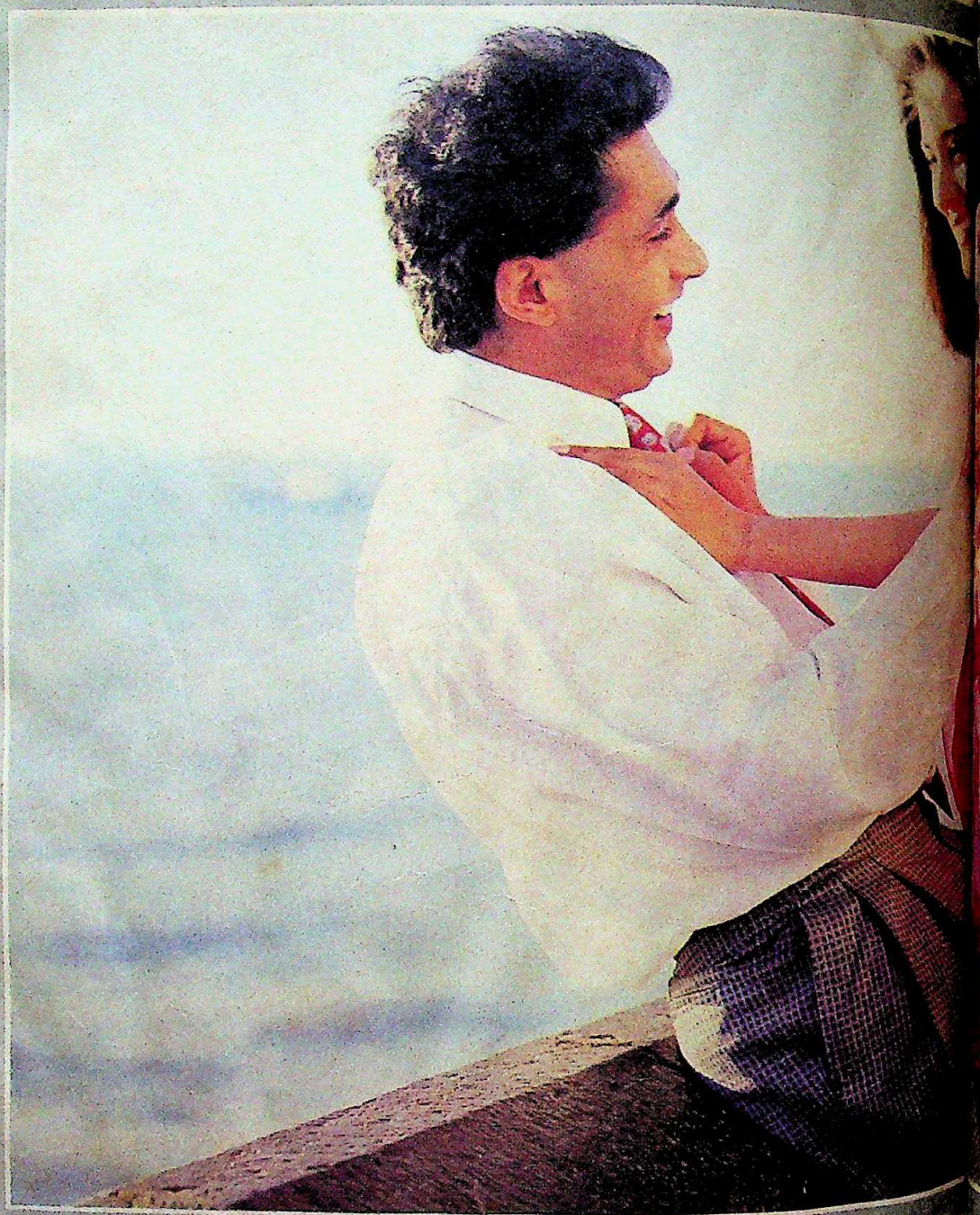

"तुम्हारा जन्मदिन और भूल जाऊँ?" वह बोली मुझे ते

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बोली मुझे तो इन्तज़ार था शाम का!"

पैन्टालोनी

जीवन के अंतरंग क्षणों में रेमण्ड

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

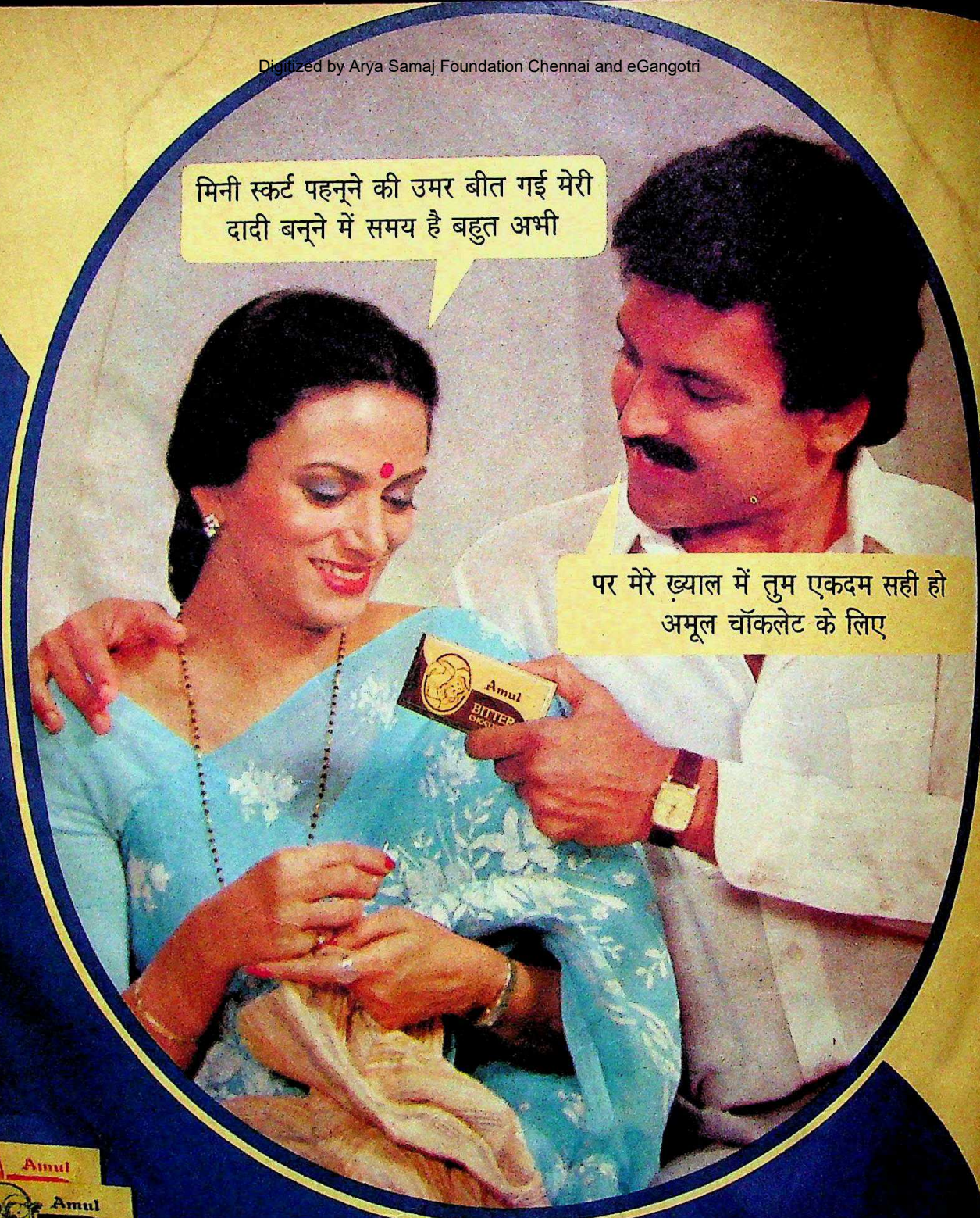

अमूल चॉकलेट
प्यार की मीठी भेंट

वितरक :
गुजरात को-ऑपरेटिव
मिल्क मार्केटिंग
फेडरेशन लिमिटेड, आणंद.

छ स्वादिष्ट चॉकलेट
अमूल मिल्क चॉकलेट, अमूल क्रिस्प, अमूल कॉफ़ी,
अमूल फ्रूट एण्ड नट, अमूल बिटर, अमूल ऑरेंज

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

के रामचंद्र

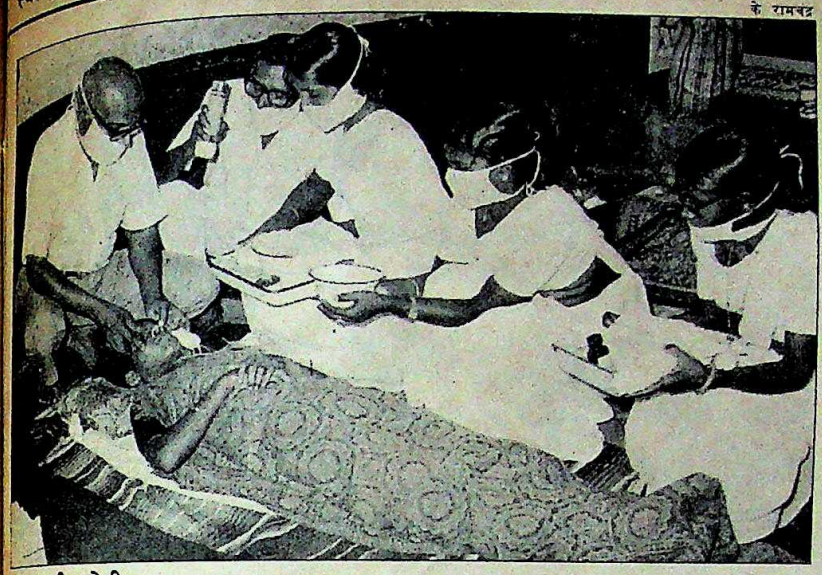

रोगी की जांच करते मोदी

डॉ. एम.सी. मोदी

खुदाई खिदमतगार

कर्नाटक में नेत्रहीनों की चिकित्सा का अप्रतिम कीर्तिमान

कलकत्ता के अनाथों के लिए जो महत्व मदर टेरेसा का है, वही कर्नाटक के नेत्रहीन गांववासियों के लिए 72 वर्षीय डॉक्टर मुरुगप्पा चेन्नवीरप्पा मोदी का है. दुनिया भर में नेत्र शल्य चिकित्सक के तौर पर प्रसिद्ध मोदी ने 45 साल से नेत्रहीनता के विरुद्ध बेहद उत्साह और निःस्वार्थ भाव से एकल अभियान छेड़ रखा है. 1986 में एक दिन के भीतर आंख के 833 ऑपरेशन करने पर उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड्स में दर्ज हुआ. ये ऑपरेशन तिरुपति में लगातार 14 घंटे में पूरे किए गए थे. मोदी अभी तक आंख के 5.79 लाख ऑपरेशन कर चुके हैं. वे यह काम निःशुल्क करते आए हैं.

मोदी के लिए यह आध्यात्मिक मिशन है. सादा जिंदगी जीने वाले इस तेजतर्रार डॉक्टर का कहना है, "खुद को मैं पुजारी मानता हूं. रोगी मेरा ईश्वर है और हर गांव मेरा तीर्थ है. ऑपरेशन की मेज को मैं पूजास्थल और उपकरणों को पूजा के साधन समझता हूं." लोगों को लौटाई गई नेत्र-ज्योति को वे ईश्वर को भेंट मानते हैं.

बीजापुर जिले के एक कन्नडभाषी साधारण परिवार में जन्मे मोदी ने 8 अगस्त 1942 को बंबई में गांधी जी की ऐतिहासिक प्रार्थना सभा में शामिल होने के बाद निजी प्रैक्टिस का कमाऊ धंधा छोड़ दिया. और नेत्रहीनों की उम्मीदें पूरी करने के लिए अपना जीवन अर्पित कर देने का फैसला कर लिया.

जन नेत्र शिविरों में डॉ. मोदी एक घंटे में 40 रोगियों का ऑपरेशन करते हैं. एक बार में वे चार रोगियों को निबटाते हैं. दोनों हाथों से काम लेने के बावजूद वे नाजुक ऑपरेशन भी बाएं हाथ से निपुणता से कर लेते हैं. पहले डॉ. मोदी अपने शिविरों में रोजाना 600 से 700 ऑपरेशन किया करते थे. पर अब कर्नाटक में वे हर रोज 200 से 300 रोगियों का ऑपरेशन करते हैं.

मोदी ने एक दिन में आंखों के 833 ऑपरेशन करके गिनीज बुक में जगह पाई है. वे एक घंटे में 40 ऑपरेशन मुफ्त करते हैं

मोदी पद्मश्री और पद्मभूषण से अलंकृत किए गए. अमेरिका के नेत्रहीन और गूंगे-बहरे लेखक हेलन केलर ने, जो 1954 में उनके एक शिविर में रह चुके हैं, मोदी से पूछा था, "क्या आपने अपने हाथों का बीमा करा रखा है?" 5.79 लाख ऑपरेशन करने के अलावा वे 50 लाख रोगियों की जांच कर चुके हैं और एक करोड़ लोगों को मुफ्त खाना मुहैया करा चुके हैं.

शुरू में मोदी को लोगों को अपना मिशन समझाने में काफी दिक्कत आई थी. डॉ मोदी बताते हैं, "गांववाले मुझसे पूछा करते थे कि अगर मैं ठीक इलाज कर लेता हूं तो फिर मुफ्त ऑपरेशन क्यों करता हूं?" मगर कुछ बुजुर्गवार नेत्रहीन गांववासी आखिरकार मान गए. मोदी ने उन पर अपने हाथों का करिश्मा कर दिखाया. उनकी नजर लौट आई. यही गांववासी उनके 'दूत' बन गए.

शुरू में उन्हें बहुत परेशानी झेलनी पड़ी. अपना डॉक्टरी बैग उठाए वे बस, साइकिल और बैलगाड़ी पर सफर करके खलिहानों और गोदामों में ऑपरेशन करने जाते. लेकिन बाद में शोहरत के साथ दान भी मिलता गया. आज मोदी के पास दुनिया का सबसे बड़ा चलता-फिरता नेत्र चिकित्सालय है जिसमें रोजाना 200 रोगियों का इलाज होता है. उनका धर्मार्थ ट्रस्ट लोगों के चंदे से ही चलता है.

अब तक 45,000 गांवों में वे इलाज कर चुके हैं. एक महीने में वे तीन शिविर लगाते हैं. हर शिविर में दो दिन ऑपरेशन के लिए निर्धारित होते हैं. वे कहते हैं, "मैं हमेशा काम में लगा रहता हूं." वे स्वास्थ्य विज्ञान पर सख्ती से अमल करते-करवाते हैं. उनके 99.5 फीसदी ऑपरेशन सफल रहते हैं. नाकामी तो रोगी की नासमझी या लापरवाही की वजह से ही होती है.

जरूरतें उनकी बहुत कम हैं. परिवार के लिए उनके पास कम ही समय बचता है. उन्हें यह भी नहीं पता कि उनकी पत्नी और बेटा गुजारा कैसे चलाते हैं. वे नम्रता से कहते हैं, "मैं तो गरीबों की खिदमत करता हूं. बाकी सभी बातों का ध्यान ईश्वर ही रखते हैं."

45 साल की सेवा के बाद भी डॉक्टर थके नहीं हैं. अब विकलांगों को आत्मनिर्भर बनाकर उनके पुनर्वास की नई परियोजना पर काम कर रहे इस जेहादी मिशनरी का कहना है, "मैं आराम कैसे कर सकता हूं जबकि मुझे पता है कि काम करके प्रत्येक मिनट में मैं एक गरीब ग्रामीण को बचा सकता हूं." उन्होंने कभी अपने नेत्रशिविर स्थगित या रद्द नहीं किए. क्या उनकी कोई आकांक्षा अधूरी बची है, यह पूछे जाने पर डॉ. मोदी कहते हैं, "मेरी एक ही ख्वाहिश है कि आखिरी दम तक मैं उपयोगी बना रहूं." नेत्रहीनों के बीच काम के उनके अथक रिकार्ड को देखते हुए यह कोई शेखी नहीं लगती.

—अनीता प्रताप

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

चंबल के डाकू गिरोह

छोटे पर शातिर

सुस्ती से लाभ उठाने में माहिर

उनकी कमजोरी ही जैसे उनकी ताकत है. चंबल के बीहड़ों और बुंदेलखंड के जंगलों में सक्रिय प्रायः सभी हथियारबंद गिरोह छोटे-छोटे ही हैं. इतने छोटे कि मध्य प्रदेश पुलिस अपने डाकू उन्मूलन अभियान की फाइलों में उनके नाम दर्ज करना भी मुनासिब नहीं समझती. इन गिरोहों में पांच से दस तक सदस्य ही हैं. कम संख्या में होने के कारण वे फुर्ती से कहीं भी आ-जा सकते हैं. इसलिए कानून के रखवालों के लिए निरंतर परेशानी का सबब बने रहते हैं.

ग्वालियर के पुलिस अधीक्षक श्यामस्वरूप शुक्ला कहते हैं, "कई बार महीनों तक वे चुपचाप बैठे रहते हैं और हमारी चौकसी में सुस्ती आते ही वारदात कर बैठते हैं." अभी हाल में डकैतों ने ग्वालियर से दो व्यक्तियों का अपहरण फिरौती वसूलने के लिए कर लिया जिसमें एक स्कूली छात्र और छतरपुर का एक धनी व्यापारी शामिल था. इसके अलावा मुरैना के बाहरी इलाके से तीन दूधियों को भी पकड़ लिया. अचानक हुई इन वारदातों के कारण पूरे इलाके में दहशत फैल गई.

'बचे-खुचे डकैत गिरोहों के उन्मूलन के लिए' पुलिस को पिछले पखवाड़े एक विशेष अभियान छेड़ने को मजबूर होना पड़ा. मध्य प्रदेश पुलिस के महानिदेशक बिराजकृष्ण मुकर्जी ने कबूल किया, "इधर सुस्ती की वजह से स्थानीय गिरोहों को अपनी कारगुजारियां करने का मौका मिल गया." लेकिन अब गिरोहों के सरदारों को पकड़वाने की इनाम राशि दुगुनी, 10,000 रु. कर दी गई है. इस पहल के अच्छे नतीजे भी निकले हैं. पुलिस ने चंबल के रक्तरंजित इतिहास के पहले सिख डाकू बंता सिंह को शिवपुरी जिले में 15 अप्रैल को मुठभेड़ में मार गिराया. उस पर 10,000 रुपए का इनाम था.

पिछले पखवाड़े छोटा जाटव गिरोह के एक सदस्य पोथी जाटव को भिंड के जंगलों में गिरफ्तार कर लिया गया. पोथी के सिर पर 5,000 रुपए का इनाम था. 3,000 रुपए के इनाम वाले डकैत बीरेंद्र सिकरवार (दुर्दांत डकैत रघुराज सिकरवार का भाई) ने मुरैना के एसपी सुरेंद्र सिंह के सामने आत्मसमर्पण कर दिया.

लेकिन इधर डकैतों की सबसे सनसनीखेज वारदात रही मुरैना शहर के बाहरी इलाके के तीन दूधियों का अपहरण. पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह ने बताया, "इसमें बैजनाथ गूजर गिरोह का हाथ होने का संदेह है." वैसे डोंगरपुर गांव के इन अपहृत व्यक्तियों के घरवालों ने बताया कि उनसे फिरौती की मांग नहीं की गई है. एक अपहृत व्यक्ति मोहर सिंह के पिता सोनेराम ने कहा," पुलिस दबाव के कारण डकैतों ने अभी तक अपनी मांग नहीं रखी है." तीनों दूधिये 31 मार्च से लापता हैं.

इससे पहले 17 मार्च को ग्वालियर के एक व्यापारी के 10 वर्षीय पुत्र दीपक का स्कूल से लौटते वक्त अपहरण कर लिया गया. पिछले पखवाड़े पुलिस उसे तभी बरामद कर पाई जब उसके माता-पिता ने अपहरणकर्ताओं को 50,000 रुपए फिरौती के रूप में दे दिए. इसके पहले 18 फरवरी को छोटा जाटव गिरोह ने 20 वर्षीय जनवेद काछी को ग्वालियर के पास एक मंदिर से अपहरण कर लिया. वह अभी भी उस गिरोह के कब्जे में है. लेकिन 3 अप्रैल को अपहृत छतरपुर के एक व्यापारी जगदीश सराफ को छुड़वाने में पुलिस अभी हाल ही में कामयाब रही है.

चंबल और विंध्य के इलाके में आजकल डकैतों के चार संगठित गिरोह सक्रिय हैं. इनके सरगना विद्या गड़रिया, बैजनाथ गूजर, छोटा जाटव और शिव कुमार उर्फ ददुआ हैं.

अक्सर साधू के वेश में रहने वाला विद्या गड़रिया केवल 27 साल का है. वह इस 'धंधे' में पिछले चार वर्षों से है. उसके गिरोह में एक महिला जयदेवी सहित छह सदस्य हैं. यह गिरोह मुख्यतः शिवपुरी और ग्वालियर जिलों में ही लूटमार करता है.

बैजनाथ गूजर ने 1982 में आत्मसमर्पण कर दिया था. लेकिन जमानत पर छूटने के बाद सितंबर 1986 में उसने मुरैना शहर में दिनदहाड़े तीन व्यक्तियों की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि तीनों ने उसके भाई के खिलाफ गवाही दी थी. छोटा जाटव की 'ख्याति' उसकी खूबसूरत महिला साथी 25 वर्षीया मीरा के कारण है जो पिछले अक्तूबर में भिंड में पति और दो वर्षीया बेटी को छोड़ आई. मीरा पर 3000 रु. का इनाम है. छोटा जाटव के खिलाफ 31 मामले दर्ज हैं और उसके सिर पर 10,000 रुपए का इनाम है. उधर विंध्य में ददुआ ही दहशत का दूसरा नाम है. मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पुलिस के साझा अभियान के बावजूद उसका 15 सदस्यीय गिरोह पांच वर्षों से बचता आया है.

लगता है डकैतों को विश्वास हो गया है कि छोटा गिरोह ही कामयाब होता है और खतरनाक भी.

—नरेंद्र कुमार सिंह, ग्वालियर से

चंबल के बीहड़: सुरक्षित पनाहगाह

प्रणात पंजियार

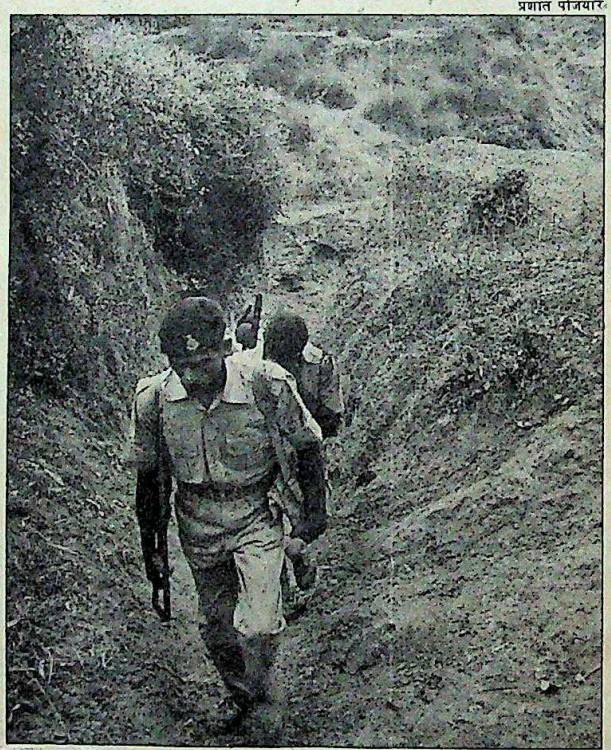

'दस्यु सुंदरी' मीरा का पति जगन्नाथ (बाएं); और सोनेराम

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'भैरव से सोहनी'

अबलाओं का बल

महिला संगीत कलाकारों का अनोखा प्रदर्शन

अविनाश पसरीचा

यह पूरी तरह महिलाओं का मामला था—बांसुरी में शास्त्रीय स्वर फूंकने वाले अधर, वायलिन पर फिसलती उंगलियां और मृदंगम तथा घटम पर थिरकते हाथ. और इनसे मिल-मिलाकर जो संगीत गूंज रहा था वह भी उतना ही मधुर और शास्त्रीय था जैसा कि होता है.

यह अनोखा संगीत समारोह—'भैरव से सोहनी'—'गीतिका' के तत्वावधान में चल रहा था. मद्रास की सिक्किल बहनें कर्नाटक शैली में बांसुरीवादन कर रही थीं. वायलिन के. उषा के हाथ में था तो मृदंगम पर आर. राव की और घटम पर सुकन्या गोपालन की कोमल थापें पड़ रही थीं. पर 'पूरी तरह' महिलाओं का यही एकमात्र कार्यक्रम नहीं था. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शन्नो खुराना, सुमित्रा गुहा, रीता गांगुली, सुहासिनी कोरटकर, अबोली सुलखे और असगरी वेगम की हारमोनियम पर संगति वासंती म्हापसेकर और तबले पर अवान मिस्त्री, नीलम शर्मा और शोभा कुदसिया ने की थी. तीन दिन के समारोह के दो दिन पूरी तरह महिलाओं के शास्त्रीय संगीत सम्मेलन को समर्पित थे.

1969 में बनी 'गीतिका' की निर्देशिका डॉ. शन्नो खुराना बताती हैं, "'83 से हमने 'सोहनी' कार्यक्रम शुरू किया. विधिवत गुरु-शिष्य परंपरा में दीक्षित और शास्त्रीय ज्ञान रखने वाली महिला कलाकारों को मंच प्रदान करना इस समारोह का खास मकसद है." संस्था इस मकसद में बहुत हद तक कामयाब भी दिखती है. चादस्वरम, सारंगी और शहनाई जैसे वाद्यों की महिला कलाकारों को सबसे पहले प्रस्तुत करने का श्रेय 'गीतिका' को ही जाता है.

पर पुरुषों का 'हस्तक्षेप' फिर भी नहीं टाला जा सकता. कम-से-कम 'भैरव से सोहनी' कार्यक्रम के तीसरे दिन 'संगीत के क्षेत्र में व्यावसायिक कलाकार के रूप में महिला संगीतज्ञों की संभावनाएं' विषय पर आयोजित चर्चा सत्र से तो यही लगा, जिसमें कुछ पुरुष संगीतविदों ने भी सहभाग किया था. बहरहाल बहस रोचक रही. कलकत्ता की डॉ. दीपाली घोष ने मुख्य पर्चा पढ़ा जिसमें उन्होंने वैदिक युग से लेकर आज तक की महिला कलाकारों की स्थिति का जायजा लिया. दीपाली का ख्याल था कि आज महिला कलाकारों के लिए संभावनाएं बढ़ी हैं. लेकिन डॉ. अनिमा बोस उनकी राय से इत्तफ़ाक नहीं रखती थीं. अनिमा आज के आर्थिक-सामाजिक ढांचे में महिला कलाकारों के प्रति दोरंगी नीति से क्षुब्ध थीं.

पर पं. विनयचंद्र मौद्गल्य उनसे असहमत थे. उन्होंने कहा कि औरतें तो हर मंच पर दिखती हैं. असली समस्या तो पुरुष कलाकारों के संघर्ष की है. शिक्षक के तौर पर गांधर्व संगीत महाविद्यालय के प्राचार्य पं. मौद्गल्य की यह भी शिकायत थी कि "हम इतनी मेहनत से महिला कलाकार तैयार करते हैं और शादी के बाद वे संगीत को तिलांजलि दे देती हैं." डॉ. रंगनायकी आयंगर ने सुझाव दिया कि एक ऐसी लॉबी बनानी चाहिए जो महिला कलाकारों का बिखराव दूर कर उन्हें संगठित कर सके. डॉ खुराना की भी यही राय थी कि महिला

सिक्किल बहनों का कर्नाटक शैली में बांसुरीवादन

पेशेवर कलाकारों को एकजुट होकर संघर्ष करना चाहिए. तबला वादिका अवान मिस्त्री पारसी समाज की इकलौती महिला कलाकार (तबला) हैं. वे अपने प्रति पुरुष कलाकारों की उपेक्षा से बेहद क्षुब्ध थीं. उन्होंने अपना वह अपमानपूर्ण अनुभव सुनाया जब किसी समारोह में पुरुष गायक ने उन्हें देखकर नाकभौं सिकोड़ ली थी.

संगीत समारोहों की आयोजक की हैसियत से सुमित्रा चरतराम का कहना था कि वे उभरती महिला कलाकार को प्रतिष्ठित मंच देना भी चाहें तो श्रोताओं का सहयोग नहीं मिलता. रीता गांगुली समीक्षकों के रवैये से दुखी थीं. उनका कहना था कलाकार कैसा गाते हैं यह तो दो सौ लोग सुनते हैं और समीक्षक जो खाका खींचता है वह दो लाख लोग पढ़ते हैं. अगर वही कलाकार को उखाड़ने पर तुल जाएं तो कलाकार क्या कर सकते हैं.

पर सबसे पते की बात कही इस विचार सत्र का संचालन कर रहे डॉ. राघव मेनन ने. उन्होंने कहा कि पुराने जमाने में एक युग लगता था प्रदर्शन के योग्य बनने में. बरसों की मेहनत के बाद कलाकार गाने की जुर्रत करते थे पर आज तो सभी रेडीमेड फार्मूला चाहते हैं. 'घराना' नाम की कोई सार्थकता ही नहीं रह जाती जबकि एक कलाकार के बाद उसका कोई वारिस ही दिखाई नहीं देता. "सच तो यह है कि आपके सोचने का मुद्दा यह होना चाहिए कि प्रदर्शनपरक व्यावसायिक कलाकार बनने के लिए किस तरह जुटकर मेहनत की जाए. जब तक स्तर उत्कृष्ट कोटि का नहीं होगा, इन मुद्दों पर बहस बेकार है."

उनसे भी माकूल विचार एक पुरुष समीक्षक ने रखे. उसने चुटकी ली, "सच तो यह है कि आज किसी प्रतिष्ठित मंच पर प्रदर्शन करना हो तो इनमें से एक-एक गायिका संगत के लिए महिला कलाकारों की जगह महमूद धौलपुरी, साबरी खां, इंदर लाल, फैयाज़ खां, रमजान खां को तरजीह देंगी." बहरहाल 'गीतिका' का दावा है कि 'भैरव से सोहनी' संगीतोत्सव ही नहीं, क्रांतिकारी कदम है.—मंजरी सिन्हा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

फोटो रानावि

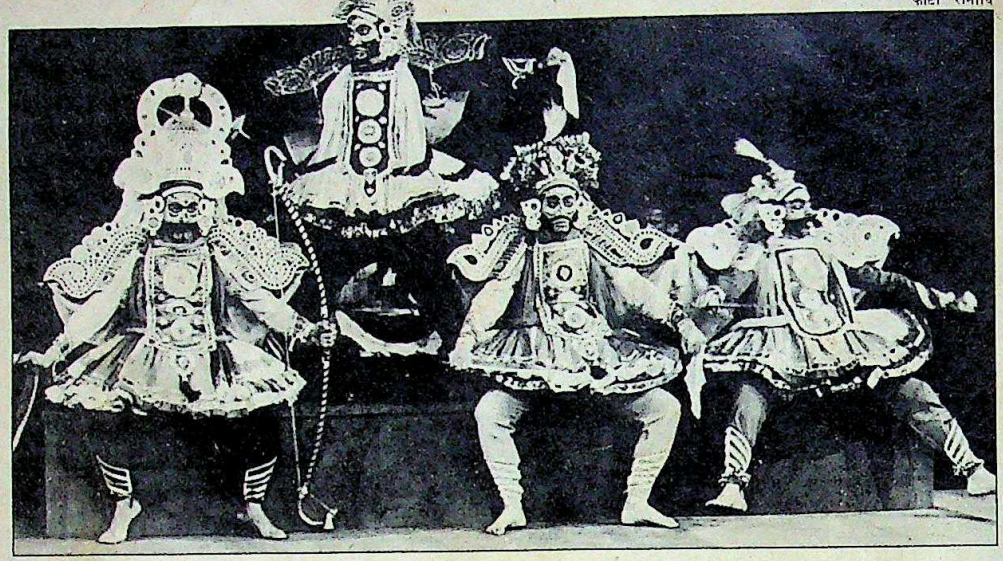

बाएं से कर्ण (तिगमांशु धूलिया), दुःशासन (किशोरजीत), दुर्योधन (निर्मल पांडे) और शकुनि (केनिथ देसाई)

रानावि दीक्षांत समारोह

इतिहास दुहराने के बहाने

समकालीन यथार्थ पर चोट करने वाले दो नाटक

दुर्योधनः प्रतिहारी! प्रतिहारीः जी महाराज! दुर्योधनः दुःशासन कहां है? प्रतिः महाराज वो तो शायद दांडी यात्रा पर निकले हैं!.... प्रतिः चलिए शकुनि महाराज. आपको महाराज दुर्योधन ने याद किया है. शकुनिः भला जानते हो किसलिए बुलाया है? प्रतिः अजी वो तो आपको इलाहाबाद के इलेक्शन के सिलसिले में बुला रहे हैं. शकुनिः अरे यह इलेक्शन क्या होता है? प्रतिः महाराज इलेक्शन तो सब जगह का कनेक्शन होता है...

दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के दीक्षांत समारोह और विद्यालय के रजत जयंती वर्ष की समाप्ति के अवसर पर 18 अप्रैल को मंचित किए गए दो नाटकों में यह पहला नाटक था—'द्रौपदी वस्त्रापहरण'. तमिलनाडु की परंपरागत तेरुक्कूत्तू लोक-शैली में खेला गया यह नृत्य-नाटक उस श्रेणी के नाटकों में से है जिनमें कथानक तो ऐतिहासिक होता है लेकिन उसका मूल संदेश समकालीन स्थिति से जुड़ा होता है. कहानी में महाभारत का वह दौर चित्रित है जिसमें द्रौपदी (वाणी सिंह) से अपने अपमान का बदला लेने को आतुर दुर्योधन (निर्मल पांडे) छल-कपट से युधिष्ठिर (राधाकृष्ण दत्त) को अपने यहां बुलाता है और शकुनि (केनिथ देसाई) की मदद से उसके साथ जुआ खेलकर पांडवों का राजपाट और उनकी पत्नी द्रौपदी को जीत लेता है. जीत के बाद वह अपने अपमान के जवाब में दुःशासन की मदद से भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतारकर उसे अपमानित करने का प्रयास करता है.

सुप्रसिद्ध तेरुक्कूत्तू कलाकार तिरु कन्नापा थंबीरन के निर्देशन में प्रस्तुत इस नाटक का हर अभिनेता पांवों में घुंघरू पहनकर नृत्य करते हुए अपनी बात कहता है. बीच-बीच में प्रतिहारी-विदूषक और सूत्रधार (संजय मिश्र) की चुटीली टिप्पणियां नाटक को सामयिक प्रासंगिकता देती चलती हैं. नाटक के पूरे दौर में मंच पर दुर्योधन का छाया रहना भी परोक्ष रूप से देश की वर्तमान हालत पर एक तीखी टिप्पणी जैसा लगता है. हालांकि मंच पर 14 कलाकारों को समय-समय पर लाया गया है पर विदूषक के अलावा केवल दुर्योधन, दुःशासन, शकुनि और द्रौपदी को ही इतना अवसर मिल पाता है कि वे अपने अभिनय की छाप दर्शक पर छोड़ पाएं. इस मामले में अंतिम दृश्य में दुःशासन की भूमिका में किशोरजीत सिंह का प्रभावशाली और तीव्र गति वाला नृत्य यकीनन दूसरों को पीछे छोड़ जाने में सफल रहा. लेकिन नाटक का अंत आते-आते दुःशासन और दुर्योधन की चाल में थकावट से जाहिर है कि यदि अगले संस्करणों में स्थान-स्थान पर चलने वाले लंबे दृश्यों को काट-छांटकर छोटा किया जाए तो दर्शक की ऊब और पात्रों की थकान दोनों से बचा जा सकता है. पात्रों की चटख रंगों वाली वेश-भूषा और गुरु कन्ना थंबीरान के संगीत ने भी नाटक को प्रभावशाली बनाने में जोरदार भूमिका निभाई है.

दीक्षांत समारोह के अवसर पर 19 और 20 अप्रैल को 'पुरवाई' टीवी सीरियल की ख्याति वाले और जाने-माने रंगकर्मी रंजीत कपूर के निर्देशन में रानावि के दूसरे वर्ष के छात्रों द्वारा पेश ज्यां ऑनुई के फ्रांसीसी नाटक 'पुअर बितोस' ने कई मायनों में मायूस किया.

नाटक में दूसरे विश्वयुद्ध के बाद फ्रांसीसी रईसों की एक डिनर पार्टी दिखाई गई है जिसमें वे लोग 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के कुछ चरित्रों जैसी विग पहनकर आए हैं. दरअसल इस पार्टी का असली उद्देश्य इतिहास की याद ताजा करने के बहाने एक स्थानीय अफसर आंद्रे बितोस (राजेश बाली) का जमकर अपमान करना है. बितोस का कसूर यह है कि वह एक ईमानदार और सख्त अफसर है और गरीब होने के बावजूद स्कूल में इन रईसजादों से बेहतर रहा. आधी दूर चलने के बाद यह कहानी बितोस के सपने के माध्यम से 1780-90 वाले दशक में पहुंच जाती है और फिर वापस वर्तमान में लौट आती है.

नाटक में दो कालों के शासक और प्रभावशाली वर्गों की मानसिकता के रिश्ते तलाशने का प्रयास किया गया है. इस उद्देश्य में निर्देशक पूरी तरह असफल तो नहीं हुआ पर कई स्थानों पर गैरजरूरी विवरणों को एकदम किताबी भाषा में पेश करके उसने नाटक के प्रभाव को यकीनन कमजोर कर दिया है. दर्शक उलझन में पड़कर ऊबने लगता है. इसके अलावा दान्तो (सीताराम) और बितोस समेत अधिकांश कलाकारों के संवाद न केवल बहुत लंबे हैं बल्कि उनकी अदायगी भी कई स्थानों पर इतनी तेज है कि वे विदेशी वातावरण में जूझते दर्शक के सिर के ऊपर से गुजरते हुए निकलते चले जाते हैं.

—विजय कपूर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पेश है : २-इन-१ सीलिंग पंखा!

और अब! वह पंखा जो आपकी मेहनत की पूरी कीमत चुकाए।

पोलर २-इन-१ सीलिंग पंखा—एक लाजवाब पंखा, दो लाजवाब फायदे: इसमें है अनोखा डबल बॉल बेयरिंग्स डिज़ाइन, जिससे यह सालों साल बेरोकटोक और बेआवाज़ चले। और कामगिरी का बेजोड़ सबूत: सबसे लम्बी गारंटी-पूरे ७ साल की।

पोलर: यानी—दुगना काम, दुगना भरोसा।

पोलर

एक सर्वश्रेष्ठ पंखा

वादे नहीं. ठोस सबूत.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Three Suit

VIMAL®
A RELIANCE PRODUCT

Dress Material

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Mudra:A RIL 42

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सिन्टेक्स - वक्त की कसौटी पर अव्वल, एकमात्र विश्वसनीय रेडीमेड पानी की टंकिया

सिन्टेक्स ने एक दशक से भी ज्यादा समय से सभी तरह की आबोहवाओं का सामना करके अपनी गुणवत्ता को साबित कर दिखलाया है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कोहिमा तक, पानी के संग्रह एवं परिवहन के सभी उपयोगोमें चल रही, लाखो सिन्टेक्स की टंकिया, अब दिन ब दिन और भी लोकप्रिय होती जा रही है !

कम्प्यूटर की सहायता से चलने वाले आधुनिक मशीनो पर अनोखे मोल्डींग प्रोसेस से बनी –सिन्टेक्स पानी की टंकियो के लाभ भी अद्वितीय है।

* वजन में हल्की * लगाने में आसान * मजबूत एवं टिकाऊ
* देखभाल से मुक्त * १०० % लीकपूफ एवं रस्टपूफ
* बहुत ही आरोग्यप्रद * १०० लिटर से २०,००० लिटर की विविध साईजो एवं आकारो में उपलब्ध * बिक्री उपरांत सेवा भारत में सर्वत्र.

अधिक जानकारी के लिये संपर्क करें :

सिन्टर प्लास्ट कंटेनर्स
प्लास्टिक्स डिव्हीजन : दि भारत विजय मिल्स लि. कलोल (उ. गुजरात) ३८२ ७२१ (भारत) दूरध्वनी: (०२७६४) २२२८, २२७४ २३५२, ३१४४, ३१४५. तार : 'SINTEX', टेलेक्स :०१२१/७२९६ BVM IN.

सिन्टेक्स - दुनियाकी नं.१ प्लास्टिक पानी की टंकिया

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उपन्यास

चिंतन और कर्म का बंधन

अब महाभारत को आधार बना कर नरेंद्र कोहली का 'महासमर'

महासमर; भाग-1- बंधन
उपन्यास
नरेंद्र कोहली
वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली
कीमत: 125 रुपए

रामकथा को औपन्यासिक रूप में प्रस्तुत करके नरेंद्र कोहली ने हिंदी साहित्य जगत को चौंका दिया था. आधुनिक दृष्टिकोण, तर्कशील प्रवृत्ति, मौलिक उद्भावनाओं, कथा चरित्रों को नई दृष्टि से देखने की तकनीक ने नरेंद्र कोहली के प्रति पाठकों के मन में अनेक आशाएं जगाई. इसलिए स्वाभाविक था कि पाठक ही नहीं, अनेक लेखक भी उनसे महाभारत को आधार बनाकर लिखे गए उपन्यासों की अपेक्षा करने लगे. 'कृष्ण सुदामा' के जीवन पर आधारित 'अभिज्ञान' ने उनकी दिशा का स्पष्ट संकेत भी दे दिया था. 'महासमर' के पहले भाग के रूप में 'बंधन' का प्रकाशन महाभारत के आख्यान को औपन्यासिक रूप में प्रस्तुत करने की उनकी योजना को स्पष्ट करता है.

'बंधन' के नायक भीष्म हैं जिनके युवा रूप से पितामह रूप के बीच घटती घटनाओं, उभरते चिंतन के द्वारा एक प्रभावी चरित्र प्रस्तुत होता है. भीष्म का चरित्र प्रख्यात है. नरेंद्र कोहली ने भीष्म प्रतिज्ञा करने वाले इस युवक के अनेक अनछुए प्रसंगों एवं उसकी चारित्रिक विशेषताओं को अपनी मौलिक दृष्टि के साथ प्रस्तुत किया है. पूरे उपन्यास में भीष्म लगातार किसी न किसी द्वंद्व में घिरे दिखाई देते हैं. वस्तुतः द्वंद्व एक ही है— संसार और वैराग्य का, परंतु वह अनेक रूपों में प्रस्तुत हुआ है. एक ओर शांतनु जैसा कामासक्त पिता है, दूसरी ओर गंगा जैसी मां है जिसे घर नहीं बांध पाया. और इन दोनों से उपेक्षित भीष्म है. वह क्या करे? मां गंगा का व्यवहार ऐसा क्यों था? पिता शांतनु पुत्र के प्रति उपेक्षा क्यों रखते थे? माता-पिता का संतान के प्रति क्या कर्तव्य है? और संतान का क्या कर्तव्य है? शासक कैसा हो? कर्तव्य और वैराग्य में कौन प्रबल है? अनेक प्रश्न हैं जिनसे भीष्म जूझते दिखाई देते हैं. भीष्म के माध्यम से ही राजनैतिक-सामाजिक प्रश्नों पर नरेंद्र कोहली का चिंतन सामने आता है. परंतु भीष्म मात्र चिंतक नहीं हैं, वे कर्मशील योद्धा भी हैं. वे चिंतन करके रुक नहीं जाते हैं, मात्र पीड़ित नहीं होते. उस चिंतन से निकलकर समुचित कर्म भी करते हैं. नरेंद्र कोहली ने इस उपन्यास में भी नायक भीष्म के रूप में चिंतन और कर्म के सामंजस्य को प्रस्तुत किया है.

भीष्म का चिंतन उन्हें सामाजिक द्वंद्व, सत्ता की लालसा, भौतिक विलास से दूर, वैराग्य और एकांत की ओर धकेलता है, परंतु उनका कर्मवीर पक्ष उन्हें समस्याओं से जूझने को बाध्य करता है. उपन्यास के आरंभ से ही कामासक्त पिता, सौतेली मां सत्यवती, सौतेले भाइयों विचित्रवीर्य और चित्रांगद तथा बाद में वे पांडु, धृतराष्ट्र, कुंती, माद्री, विदुर आदि के लिए भौतिक कर्म में रत दिखाई देते हैं. वे बार-बार अपने से ही प्रश्न करते हैं, क्या वे बंधनों से स्वयं को मुक्त कर पा रहे हैं? क्या बंधन उन्हें निरंतर कसते नहीं जा रहे हैं?

> **"मद्यप और व्यभिचारी लोगों के हाथों में सत्ता आ जाएगी तो कौन-सा दुराचार होने से रह जाएगा. हत्याएं नहीं होंगी या बलात्कार नहीं होंगे? जब ऐसे निर्लज्ज पापी शासक होंगे तो कोई न्याय मांगने कहां जाएगा?"**
>
> 'महासमर' (पृष्ठ 398)

भीष्म जीवन के इस खेल से अलग रहना चाहते हैं परंतु कर्तव्यबोध उन्हें अलग नहीं होने देता. उपन्यास के अंत में द्वैपायन के आश्रम में मुक्ति की इच्छा से जाती हुई सत्यवती भीष्म को अपने बंधन से मुक्त करने की घोषणा करती है, परंतु क्या भीष्म मुक्त हो पाते हैं? क्या सचमुच सत्यवती भीष्म को बंधन से मुक्त करती है? क्या भीष्म जिस मुक्ति की कामना युवावस्था से कर रहे हैं, वह उन्हें वृद्धावस्था में भी मिल पाती है? भीष्म को मोह नहीं है फिर भी कर्तव्यवश वे सांसारिक बंधन में बंधे हुए हैं.

'बंधन' में मात्र भीष्म या उनका द्वंद्व नहीं है. अनेक चरित्र और उनके साथ जुड़े प्रश्न भी हैं. भोग और कर्तव्य के बीच झूलते शांतनु हैं, अपने स्वार्थ के लिए सत्ता का खेल खेलती और बाद में हताश सत्यवती है, प्रतिशोध की ज्वाला में जलती अंबा है, निरीह जीवन जीती हुई अंबालिक है, घोर स्वार्थ और सत्ता में डूबे धृतराष्ट्र और गांधारी हैं, निवीर्य पांडु हैं, विरक्त कृष्ण द्वैपायन हैं, पीड़ित कुंती और माद्री हैं. अनेक चरित्र हैं और उनसे जुड़े सामंती जीवन के अनेक पक्ष हैं.

'महासमर' में नरेंद्र कोहली ने पौराणिक आख्यान का मात्र पुनर्लेखन नहीं किया है, आज की सामाजिक विसंगतियों की विचारपूर्ण चर्चा भी की है. सामाजिक मूल्यों के संदर्भ में एक निरंतर चिंतन इस उपन्यास में धारा के रूप में प्रवाहित होता है. उनका मूल चिंतन और चिंता मूल्यों के ह्रास की है. कुछ भी गलत देखकर लेखक के मन में जैसे एक खीझ पैदा होती है. वही खीझ इस उपन्यास में अद्यांत विद्यमान है. परंतु रामकथा में जैसे राम मूल्यों की स्थापना का सार्थक प्रयास करते हैं, भीष्म वैसा चरित्र नहीं है.

'महासमर' के लेखक के पास सधी हुई भाषा है जो चिंतन को रुकने नहीं देती है. लेकिन इस उपन्यास में मात्र सामंती जीवन ही चित्रित हुआ है. उपन्यास में राजा है, उसके सुख-दुख हैं, राजमहलों के षड्यंत्र हैं, परंतु प्रजा गायब है. क्या राजमहलों में घटती घटनाओं या राजपुत्रों के चरित्र का प्रजा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? क्या जनता तब इतनी निस्पृह थी? लगता है जैसे उपन्यास के परिवेश का एक हिस्सा कट गया है. उपन्यास में उस समय का दरबारी चिंतन तो है परंतु आम समाज का जीवन बहुत कम है, न के बराबर. आशा कर सकते हैं कि अगले खंडों में राजा के साथ प्रजा भी होगी. एक महल की नहीं, पूरे परिवेश की कथा होगी. रामकथा का कथानक महाभारत की तुलना में अधिक विस्तृत नहीं था. देखें नरेंद्र कोहली इस विशाल फलक को कहां तक समेटते हैं.

—प्रेम जनमेजय

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

निबंध

सृजन के मूल्यों की पकड़

साही के निबंध प्रगतिवादियों की आंखें खोलते हैं

छठवां दशक
निबंध
विजयदेव नारायण साही
हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद
पृष्ठ-362; कीमत-80 रु.

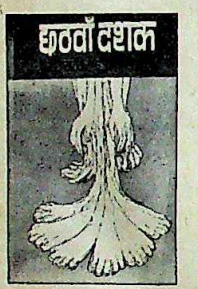

कवि आलोचक विजयदेव नारायण साही के आलोचनात्मक विचारों का स्वातंत्र्योत्तर हिंदी आलोचना में जोरदार स्वागत हुआ है. उन्होंने प्रश्नों, बहसों, गोष्ठियों तथा दलों की दलबंदी से अनवरत जूझते हुए हिंदी आलोचना के नए मूल्यों तथा मानों के लिए मार्गदर्शन का विशिष्ट कार्य किया है. 'तीसरे सप्तक', 'मछलीघर' और 'साखी' में उनका कवि कर्म मौजूद है पर कवि केंद्रित 'जायसी' पर उनकी जैसी आलोचना पुस्तक आई है उस टक्कर और वजन की मुक्तिबोध की आलोचनात्मक कृति 'कामायनी पुनर्विचार' को छोड़कर कोई और पुस्तक नहीं है. प्रगतिवादी आलोचकों से उनकी आलोचना दृष्टि इस बात में भिन्न है कि वे मूल्यों को बाहर से नहीं झोंकते बल्कि कृति के भीतर से ही अन्वेषित करते हैं.

साही के दो निबंध—जिनका हिंदी आलोचना में ऐतिहासिक महत्व है तथा जिन्होंने हिंदी के नवीन समीक्षाशास्त्र को बहुत-सा नया चिंतन है— इस निबंध संकलन में मौजूद हैं. ये उल्लेखनीय निबंध दो हैं—'लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस' तथा 'शमशेर की काव्यानुभूति की बनावट'. इनमें से पहला निबंध 'नई कविता' पत्रिका के 1960-61 के संयुक्तांक 5-6 में प्रकाशित हुआ था. उस समय इस निबंध ने आचार्यों, श्रीमानों और पाठकों में भारी तहलका मचा दिया था.

'लघुमानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस' यह लंबा निबंध छायावाद से नई कविता तक के युग की गंभीर वैचारिक यात्रा है. 'लघुमानव' से जुड़े तमाम प्रश्नों की शवपरीक्षा में वे प्रवृत्त होते हैं और पाते हैं कि जो लोग साहित्य को मूलतः मानव मूल्यों से संबद्ध मानते हैं और 'इसी में साहित्य की सार्थकता देखते हैं, उनके ऊपर एक सैद्धांतिक या दृष्टिपरक जिम्मेदारी होती है'. यही जिम्मेदारी बार-बार सामाजिक संदर्भों में बदलते, निर्मित होते मानव को परिभाषित करने की मांग करती है.

'लघुमानव' का जो ढांचा निर्मित होता है, उसमें छायावाद का 'रूप लघु की महानता का है, तीसरे दशक में लघु की महिमा का है और उसके बाद की कविता में 'लघु के महत्व' का है (पृ. 316). कहना न होगा कि साही के इस लघुमानव सिद्धांत पर प्रगतिवादियों ने भारी एतराज उठाए.

'शमशेर की काव्यानुभूति की बनावट' में काव्यानुभूति के बुनियादी सवाल को उठाते हुए साही कहते हैं, "नई कविता की बहसों में यह मान्यता अंतर्भूत रही है कि न सिर्फ कविता का ऊपरी कलेवर बदला है या नए प्रतीकों या बिंबों या शब्दावली की तलाश हुई है बल्कि गहरे स्तर पर काव्यानुभूति की बनावट में ही परिवर्तन आ गया है." (पृ. 195). कविता में यह जो 'मलार्मीय विडंबना' घटी है, साही उसका सूक्ष्म और गहन विश्लेषण शमशेर को आधार बनाकर करते हैं. उनकी निगाह में यह बात साफ है कि 'समूची नई कविता को ठीक-ठीक देखने के लिए नई कविता के प्रतिमान की जरूरत नहीं है, बल्कि कविता के नए प्रतिमान की जरूरत है."

इस पुस्तक में 'साहित्य और राजनीति', 'साहित्य में गतिरोध', 'साहित्यकार: उसका परिवेश', 'हिंदी की दो पीढ़ियां' और युग परिवर्तन' 'जनवादी साहित्य-1-2' 'नितांत समसामयिकता का नैतिक दायित्व-1-2' जैसे निबंध उनकी सैद्धांतिक वैचारिकता के दृष्टिकोण को सामने लाते हैं. 'मार्क्सवादी समीक्षा और उसकी कम्यूनिस्ट परिणति' 'आजीविका और आश्रय' जैसे लेख वैचारिकता के द्वंद्वात्मक विकास को दर्शाते हैं. समीक्षा दृष्टि कितनी बेबाक होनी चाहिए इसका परिचय 'काव्य-धारा: एक युयुत्स समीक्षा' 'मैदान, पर्वतमालाएं और राजनगर' 'हाथों में टूटी तलवारों की मूठ' 'लेखकों का दुख सुख: उनके नाम खत' 'अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग और अभिव्यंजना की कुछ समस्याएं' जैसे निबंध देते हैं. 'परिमल' विचार गोष्ठियों तथा 'आलोचना' पत्रिका के इन निबंधों में उस प्रगतिशील चिंतन के प्रकाशपुंज निहित हैं जिनसे हिंदी समीक्षा को नई दिशा मिली है. साही का विश्वास दिमागी बुखार को कम करने या बढ़ाने में न था. उनका सच्चा विश्वास साहित्य और जीवन को उसकी द्वंद्वात्मक प्रक्रिया में समझना-समझाना था. उनकी यही चिंता उन्हें मूल्यों के संकट का एहसास कराती है और जमे हुए प्रतिमानों को चिंतन की उष्मा से पिघलाकर वे नया रूप देते हैं. उनमें नए जीवन स्पंदन की सृजनात्मक धड़कन की अर्थ निष्पत्ति करते हैं.

साही के इन निबंधों से स्पष्ट है कि समूचे आधुनिक साहित्य को समझने के लिए उसके सही वैचारिक आधारों की समझ जरूरी है. नई कविता एक बौद्धिक उठान से जन्मती है— उसका चिंतन मात्र कविता के विश्लेषण से सुनिश्चित नहीं किया जा सकता क्योंकि नई कविता की विचार प्रक्रिया मूलतः भावात्मक न होकर विचारधारात्मक है. जो लोग आज नई कविता के वैचारिक आधार को बूर्जुआ प्रगतिशीलता कहकर संतुष्ट हैं उनके लिए साही के ये निबंध आंख खोलने वाले हैं. दिमागी तनाव को रोपने वाले हैं.

नई कविता आंदोलन का संगठनात्मक आधार 'परिमल' विचार गोष्ठी तथा 'नई कविता' पत्रिका रहा है. और इस आधार को प्रगतिवादी अमेरिकी गृहयुद्ध की विचारधारा का नाम देकर निकम्मा, मानवद्रोही सिद्ध करना चाहते हैं. इस पूरी स्थिति-परिस्थिति के बोध के लिए साही के ये निबंध ऐतिहासिक दस्तावेज सरीखे हैं.

—कृष्णदत्त पालीवाल

"अब लोगों की दिलचस्पी उन कुहराम वाली भट्ठियों में ज्यादा हो गई है जिनमें साहित्य का कच्चा माल सांचों में ढालने के लिए पिघलाया जाता है. चूंकि छठे दशक के पिघलाने वाले ताप में ये लेख लिखे गए, इसलिए इनमें उस वक्त की गर्मी मौजूद है"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

सरताजों में सरताज

एक्साइड एम एक्स
मोटरसाइकल व स्कूटर बैट्री

एक्साइड एम एक्स–तकनोलोजी का नन्हा-सा कमाल। जापानी और अर्न्तराष्ट्रीय मानदंड के अनुकूल। एक्साइड के शोध द्वारा खास भारतीय वातावरण और आजकल की ईंधन-सक्षम वाहनों के लिये सर्वोत्तम बनायी गयी।

एक साल की गारंटी और देश भर में फैले हुए विशालतम एक्साइड डीलर समूह का समर्थन भी। एक्साइड एम एक्स पहुँचाती है आप तक एक्साइड के अनोखे फायदे–बैट्री संग आपको मिलती है सम्पूर्ण विश्वसनीयता, निर्भरता और निरन्तर सेवा की सुविधाएं।

एक्साइड एम एक्स रेंज

6 MX 4-2A	इंड सुजुकी, यामाहा १००
12,MX 2.5 L-C	हीरो होंडा
12 MX 5 L-B	काइनेटिक होंडा, बजाज कावासाकी
12 MX 5.5	यामाहा ३५०, एनफील्ड सुपरस्टार

एक्साइड चलती रहे हर दम... चाहे बाकी जायें थम

एक्साइड इंडिया का उत्पादन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

ARTIG 510

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आपके 'सफ़ारी' की चाभी खो जाए, तो बस भगवान बचाए.

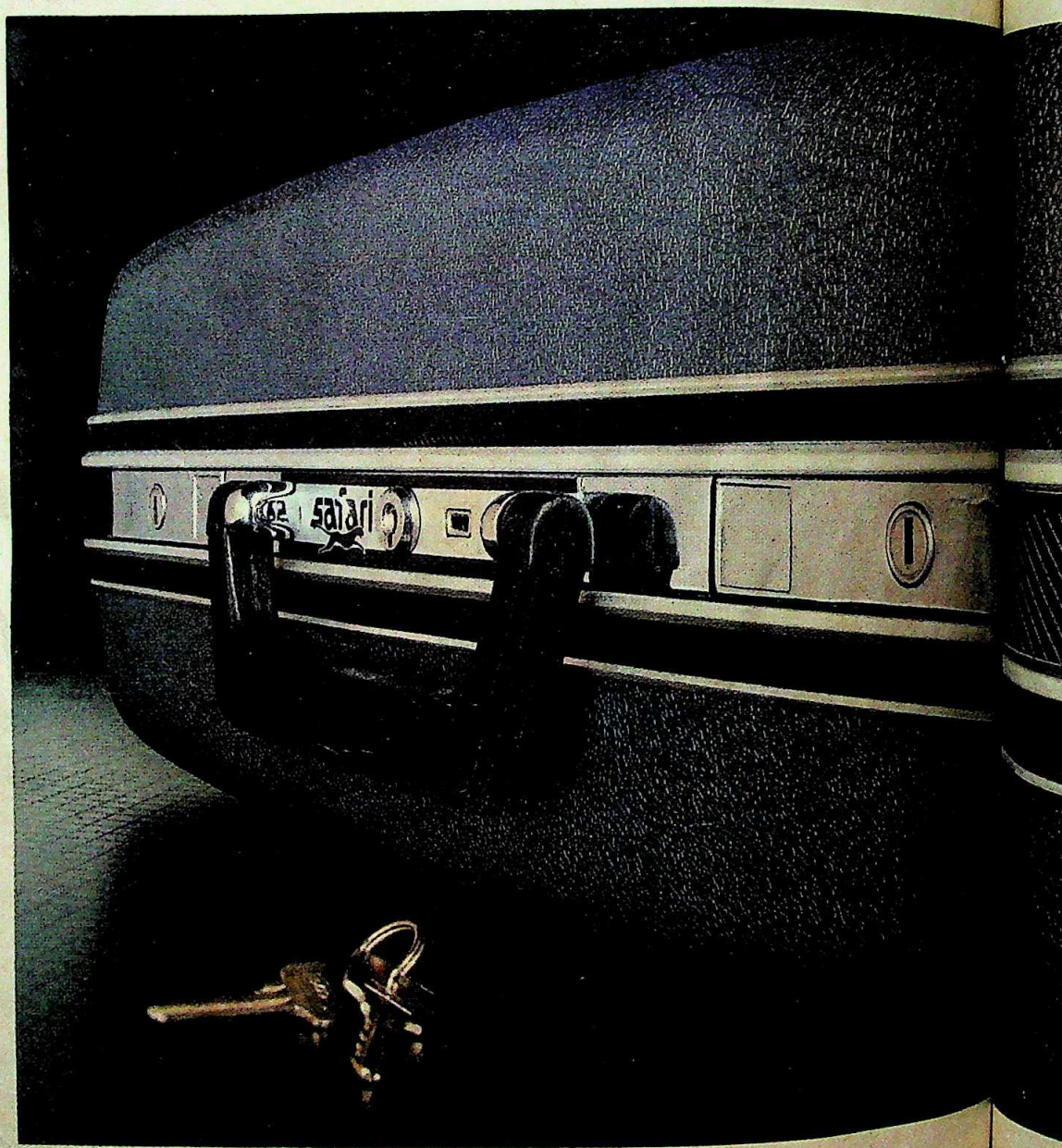

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हर सफ़ारी का बीच वाला ताला ६ लीवर का वॉल्ट-ताला होता है.

दूसरे सूटकेसों में ४-लीवर या ५ लीवर के मामूली ताले लगाये जाते हैं और ऐसे तालों को खोलना सफ़ारी के मुकाबले १० गुना आसान होता है.

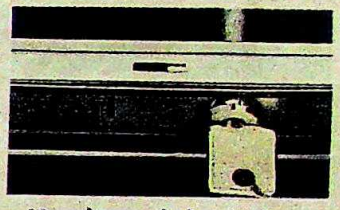

सिर्फ़ इतना ही नहीं, सफ़ारी में ताले के अंदर की "लॉकिंग स्लाइड" ठोस स्टील के एक चैनल में बिठाई गयी होती है. इसीलिए तो ताला तोड़नेवालों की दाल नहीं गलती.

इसी तरह आप देखेंगे कि आपके सफ़ारी की हर चीज़ पर बहुत ही बारीकी से ध्यान दिया गया है. चेन गार्ड की ही बात लीजिए. हमने इसका डिज़ाइन इस तरह बनाया है कि इसमें चेन जोड़ने के लिए, आपको चाभी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी.

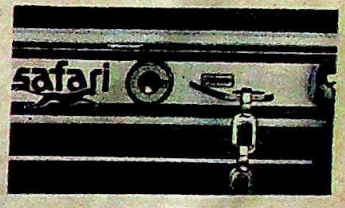

या फ़िर देखिए 'गैलेक्सी 2001' सीरीज़ के हमारे सूटकेस. 'ट्विन राइट-साइड-अप' की खास तकनीक की वजह से ये सूटकेस तभी खुल पाते हैं जब उन्हें सीधा रखा गया हो. सूटकेस खड़ा रखा हो और कोई उसे खोलने की कितनी ही कोशिश करे, तब भी वह खुलनेवाला नहीं.

ऊंची क्वालिटी बनाये रखने के लिए हम हमेशा से सूटकेसों की सबसे कड़ी जांच करते आये हैं. इसीलिए तो, आप तक पहुंचने से पहले हर सूटकेस की ९० अलग-अलग बातों के लिए जांच कर ली गयी है, इस बात की हमें तसल्ली रहती है.

जहां तक तालों की बात है, अपना एक छोटा-सा राज़ आपको बता ही दें.

अगर कभी गलती से आपके सफ़ारी की चाभी खो ही जाए तो आप उसे लेकर सीधे अपने शहर के सफ़ारी ऑफिस में चले आइए.

वहां आपको मिलेगा एक मैकेनिक जिसे फैक्टरी में हमने पूरे दो हफ़्ते यह सिखाया है कि ऐसे में सफ़ारी के ताले कैसे खोले जाएं.

safari

भरी हैं इसमें सैकड़ों खूबियां.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Enterprise/SI/05 Hn

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

◆ पेरिस की टीमटाम अब दिल्ली में भी आ पहुंची है. और इसका श्रेय एक देसी डिजाइनर 30 वर्षीय **हेमंत सागर** को है. फ्रांस के एक फैशन स्कूल से निकलने के बाद हेमंत ने एक पार्टनर दीदीयर लेकॉने के साथ मिलकर पेरिस में डिजाइन का कारोबार शुरू किया. और पिछले पखवाड़े दिल्ली लौटकर इस जोड़ी ने भारत में फैशन की दुनिया के लोगों को दिखा दिया कि फैशन क्या होता है. हेमंत कहते भी हैं, "इस कारोबार में कल्पना को मूर्त रूप देना होता है, इसमें आनंद की अनुभूति होती है." कपड़े पर हाथ से की गई उनकी कढ़ाई लाजवाब तो है ही, महंगी भी है. हेमंत कहते हैं, "मैं तो जन्म से ही शांतिवादी हूं. इसका इजहार मैं फूलों के जरिये करता हूं." वे भारत में फैशन डिजाइन बेचने वाले हैं.

हेमंत (बाएं) मॉडलों के साथ

◆ उसके बदले हुए नाम ने परदे पर चमत्कार कर दिया. तीन साल पहले तमिल फिल्म निदेशक बालू महेंद्र जब 21 वर्षीया सुधा रानी को खोजकर लाए तो उन्होंने उसका नाम बदलकर **अर्चना** रख दिया. तेलुगु फिल्मों की इस तारिका ने उनकी फिल्मों (नीगल केटवै, रट्टेवाल कुरुवि) में मध्यवर्गीय कामकाजी लड़की अथवा गृहिणी की भूमिका बखूबी निभाई है. महेंद्र की एक फिल्म 'वीड्' (घर) में ऐसी ही एक भूमिका के लिए पिछले पखवाड़े उसे 35वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा के अनुसार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुन लिया गया. फिल्म में उसने एक संवेदनशील और साहसी शहरी औरत की भूमिका निभाई है. अर्चना का कहना था, "मैं इतनी रोमांचित हुई कि उसका एहसास अभी भी खत्म नहीं हुआ."

अर्चना: राष्ट्रीय सम्मान

श्याम टेकवानी

◆ 'हरे रामा हरे कृष्णा' से लेकर 'सत्यम् शिवम् सुंदरम्' फिल्मों वाली चंचल लड़की से उम्मीद थी कि वह किसी उभरते कलाकार को एकाध गुर बता देगी. पर इसके उलट अभिनेता मजहर खान से ब्याही **जीनत अमान** ने अपना ध्यान स्कूली बच्चों पर केंद्रित किया है. इन दिनों वे शिक्षा संबंधी रिकार्डिंग के काम में जुटी हुई हैं. यह रिकार्ड इसी महीने सीबीएस कंपनी ने जारी किया. इसके जरिये बच्चों को अंग्रेजी के सही उच्चारण की सीख दी जा सकेगी. दिलचस्प यह है कि इसके लिए उन्हें उनके डेढ़ साल के बेटे अज्ञान ने प्रेरित किया. जीनत कहती हैं, "मैंने सोचा कि यह तोहफा उसे दूंगी." इसीलिए वे अंग्रेजी के ककहरा और गिनती के साथ बालगीत शुद्ध उच्चारण के साथ गा रही हैं. उनका कहना है, "मैं हमेशा अभिनय थोड़े ही करती रहूंगी!"

जीनत: ककहरा, पहाड़

प्रशांत पंजियार

◆ फिल्म अभिनेता **दिलीप कुमार** जब पाकिस्तानी दौरे पर थे तो रावलपिंडी के एक निवासी ने इस आशंका में कि कहीं वे 'संवेदनशील इलाकों' की तस्वीरें खींचकर भारत न ले जाएं, उनके खिलाफ एक मुकदमा दायर कर दिया. और सिविल जज ने दिलीप को अदालत में पेश होने के लिए सम्मन भी जारी कर दिया. इसके बाद मुकदमा रहस्यमय तरीके से वापस ले लिया गया. लेकिन 45 साल बाद अपने गृहनगर पेशावर गए दिलीप साहब इस पूरे विवाद से अनजान ही रहे. वे कहते भी हैं, "पाकिस्तान में किसी ने मुझसे कहा कि कुछ लोग मेरी यात्रा का विरोध कर रहे हैं पर मेरे चाहने वालों की गर्मजोशी के सामने सारा विरोध फीका पड़ गया."

दिलीप पाकिस्तान में दोस्त के साथ

किरण: प्रधानमंत्री से प्रेरणा

प्रशांत पंजियार

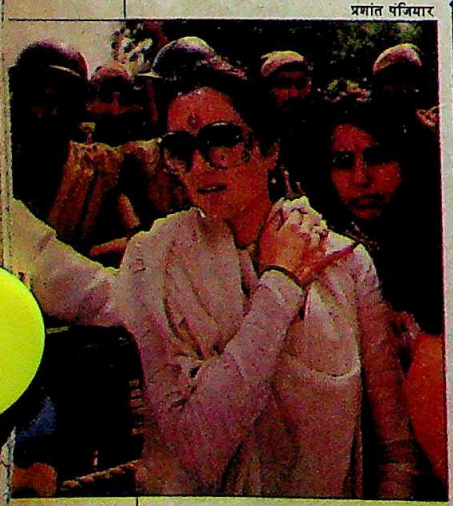

◆ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की पुत्रवधू 30 वर्षीया **किरण चौधरी** की राजनैतिक पृष्ठभूमि ही तगड़ी नहीं, वे खूबसूरत भी हैं. उनके पति सुरिंदर सिंह राज्यसभा सदस्य हैं. 12 साल पहले ब्याही किरण कहती हैं, "मैं अपने पति के कैरियर से ही जुड़ी नहीं बल्कि अब अपने पैरों पर भी खड़ी हो गई हूं." अब महिला कांग्रेस की यह आकर्षक कार्यकर्ता राजधानी में गरीब औरतों की वकालत करती घूम रही है. पिछले पखवाड़े किरण ने, जो सुप्रीम कोर्ट की वकील भी हैं, भारत में आतंकवाद को भड़काने की पाकिस्तानी साजिशों के खिलाफ प्रदर्शनकारियों की एक भीड़ की

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

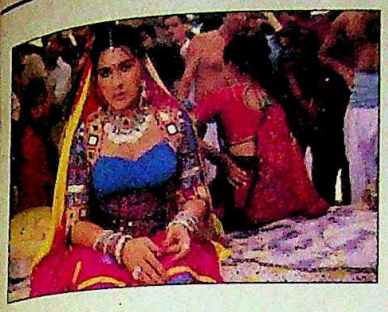

कभी शोले कभी शबनम

भारतीय फिल्मोद्योग का आज का नजारा कुल मिलाकर विरोधाभासी है. फिल्म निर्माण पर तो भारी-भरकम रकम लग रही है पर बनी हुई फिल्मों का डिब्बे से बाहर निकलना मुश्किल होता जा रहा है. इस हालत का विस्तृत विश्लेषण और 75 साल के इतिहास का लेखा-जोखा

आवरण कथा.....40

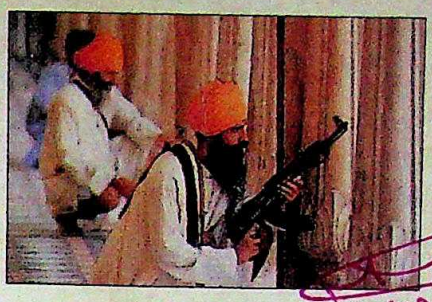

मरने मारने का माहौल

उग्रवादियों ने पिछले पखवाड़े स्वर्ण मंदिर के भीतर से सीआरपी के एक अफसर पर गोलियां चलाईं और मोर्चा जमाकर बैठ गए. सीआरपी और कमांडो ने भी मंदिर के इर्द-गिर्द घेरा कस दिया. मौके पर जाकर लिखी रिपोर्ट और उग्रवादियों तथा पुलिस मुठभेड़ के चित्र.

आजकल.....22

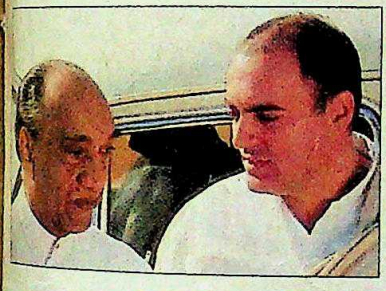

करार कामयाबी की राह पर

पिछले पखवाड़े की घटनाएं भारत-श्रीलंका समझौते के लिए महत्वपूर्ण थीं. श्रीलंका में प्रांतीय परिषदों के चुनाव और जनता विमुक्ति पेरमना के साथ हुए समझौते ने भारत सरकार को मजबूर कर दिया है कि वह जल्दी ही तमिल टाइगरों से निबटे.

पास-पड़ोस.....51

सर्वोच्च सत्ता का नया शिखर

राजीव के सत्ता में आने के बाद से ही मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रभाव बढ़ता रहा है और अब तो यह जैसे 'सुपर मंत्रिमंडल' में ही तब्दील हो चुका है. सचिवालय का दबदबा कितना है और कहां तक उसके हाथ पहुंचे हुए हैं, इस पर एक रिपोर्ट.

विशेष लेख.....90

मालिकों की टेढ़ी नजर

मालिकों से अपनी हर बात मनवा लेने के मजदूर संघों के सुनहरे दिन अब लद चुके. इसके लिए कुछ हद तक संघों के लोग भी जिम्मेदार हैं. बाजार में बढ़ती प्रतियोगिता से मजबूर नियोक्ता अब अपनी मांगें रखते हैं और कर्मचारियों को उन्हें पूरा करना पड़ता है.

कारोबार.....106

बूंद से मोती बनाने का अभियान

आम लोगों को इसकी जानकारी नहीं है लेकिन भारतीय खेल प्राधिकरण देश के सुदूर इलाकों में नई खेल प्रतिभाएं ढूंढ़ निकालने के अभियान में जुटा हुआ है. और कुछ क्षेत्रों में तो इन असाधारण प्रयत्नों के खूबसूरत परिणाम भी सामने आने लगे हैं.

विशेष लेख.....110

अगले पन्नों पर

कसौटी.....9
राजरंग.....12
तेवर.....14
हिंदोस्तां हमारा.....19
बीता पखवाड़ा.....21
आजकल
पंजाब: मरने मारने का माहौल.....22
राजकपूर: दवाओं और दुआओं के सहारे..27
जनता पार्टी: यादवी संघर्ष.....29
कर्नाटक: जीते मगर आन न रही.....30
जम्मू: हौलनाक हादसे से हड़कंप.....32
बिहार: खतरा बरकरार.....33
बिहार: मुक्ति अभियान.....34
मध्य प्रदेश: पराक्रमी पुलिस.....35
आखिरी बात.....36
आवरण कथा
भारतीय सिनेमा उद्योग:
कभी शोले कभी शबनम.....40
पास-पड़ोस
श्रीलंका: करार कामयाबी की राह पर.....51
दक्षिण भारत परिशिष्ट
परंपरा और परिवर्तन का परिदृश्य.....53
राज्य-दर्पण.....85
खास रपट
बीरबहादुर सिंह:
सत्ता और संपर्क की सटीक समझ.....86
विशेष लेख
मंत्रिमंडल सचिवालय:
सर्वोच्च सत्ता का नया शिखर.....90
जीवन शैली
पप्पी संस्कृति:
पैसे से प्रतिष्ठा पाने की सनक.....96
खास रपट:
भारत-पाक रिश्ते:
पल में तोला पल में माशा.....102
व्यापार चक्र.....105
कारोबार
मजदूर संघ: मालिकों की टेढ़ी नजर.....106
विशेष लेख
विशिष्ट खेल कार्यक्रम:
बूंद से मोती बनाने का अभियान.....110
शिक्षा
बिहार: मिथिला में 'महाभारत'.....114
किताबें.....115
रहन-सहन
मेघालय: मोर्चे पर मर्द.....117
धर्म
तंजावूर: लुप्त होता अनूठापन.....118
रंगमंच
विकलांगों का थिएटर.....124
विकास
उत्तर प्रदेश: गांवों को निगलते शहर.....126
टीवी
दूरदर्शन:
बड़ी योजनाओं के छोटे नतीजे.....130
अपराध
कर्नाटक: बड़ी कामयाबी.....132
चर्चित चेहरे.....136

आवरण: भवान सिंह

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कलकत्ता का एक शान्त इलाका। सुबह की खुशनुमा हवा में संगीत की गूँज। उत्तर प्रेदश के बदायूँ ज़िले के नौजवान गायक राशिद खाँ अपना रियाज़ शुरू करते हैं। उन्हें विभिन्न रागों की तालीम देतेहुए उस्ताद निसार हुसैन खाँ बेहद फख्र महसूस करते हैं और अब उन्हें पूरा यकीन है कि प्रतिभा के फूल खिलते रहेंगे। गुरु-शिष्य के बीच ६० साल के अन्तर को इस तानपूरे ने पाट दिया, जो उस्ताद निसार हुसैन खाँ को अपने दादा से मिला था और अब उनके शागिर्द के सुनहरे भविष्य का शिल्पकार है। यह गुरु-शिष्य परम्परा की अनुपम मिसाल है। राशिद खाँ के संगीत के जादू में डूबे, उस्ताद निसार हुसैन खाँ को पिछले दशक की याद हो आती है, जब आई टी सी उनकी मदद के लिए आगे आयी...

बदायूँ के राशिद खाँ। उस्ताद निसार हुसैन खाँ परेशान थे कि उनके प्रतिभावान शागिर्द की आवाज़ दुनिया के शोर में गुम होकर रह जाएगी।

तभी आई टी सी ने संगीत रिसर्च अकादमी की स्थापना करके निराशा के अंधेरे में आशा का दीप जलाया।

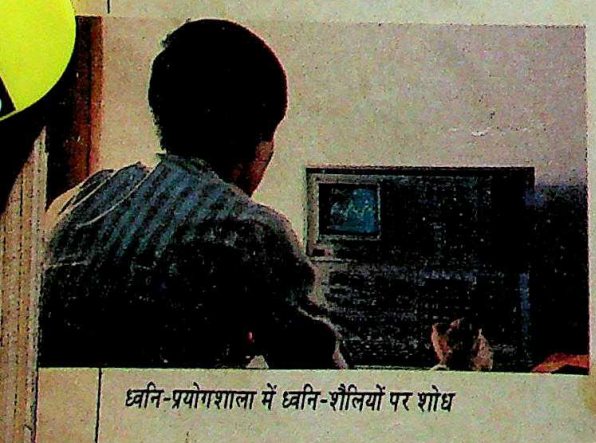

ध्वनि-प्रयोगशाला में ध्वनि-शैलियों पर शोध

समुचित संरक्षण के अभाव में भारतीय शास्त्रीय संगीत मंद पड़ता जा रहा है—यह महसूस करतेहुए आई टी सी ने संगीत रिसर्च अकादमी की स्थापना करके गुरु-शिष्य परम्परा को पुर्नजीवित किया। सन् १९७८ से विभिन्न घरानों के प्रवीण संगीतज्ञ यहाँ रहतेहुए, संगीत की खिलती हुई प्रतिभाओं को तालीम दे रहे हैं।

संगीत रिसर्च अकादमी में परम्परा और तकनीक का खूबसूरत गठबंधन हुआ है। गुरु-शिष्य शिक्षा-प्रणाली के साथ-साथ यहाँ आधुनिक ध्वनि-प्रयोगशाला और ग्रंथागार भी है, जहाँ पुराने ज़माने की अमूल्य रिकॉर्डिंग संरक्षित हैं।

शास्त्रीय संगीत और नृत्य के विकास के लिए आई टी सी दिल्ली में संगीत सम्मेलन आयोजित करती है और इसी तरह अन्य शहरों में भी समारोह आयोजित किए जाते हैं। भारतीय कला और संस्कृति के प्रचार-प्रसार का यह प्रयास, राष्ट्र के प्रति आई टी सी की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

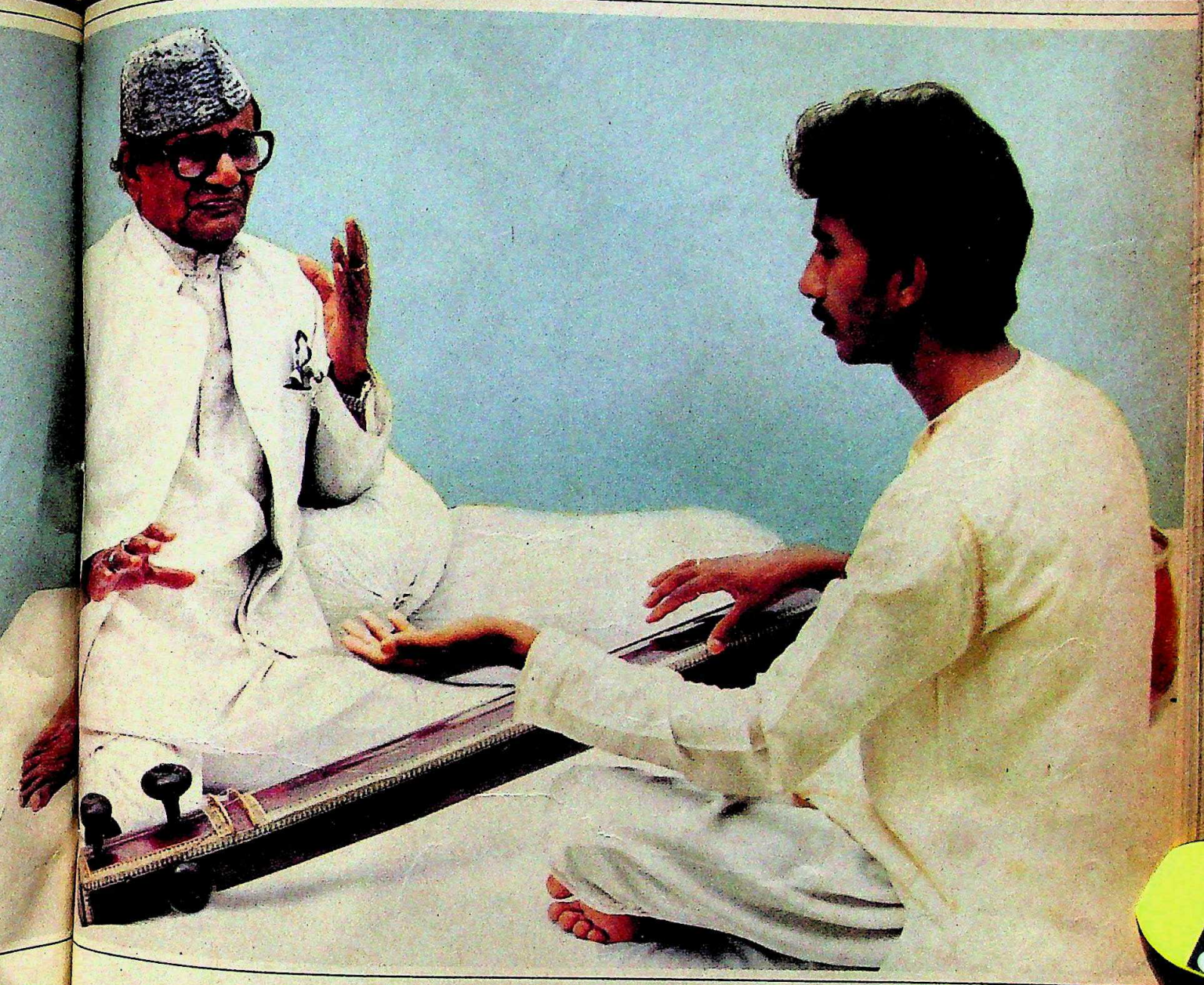

को आत्मसम्मान और गरिमामय जीवन देने के लक्ष्य में आई टी सी के प्रयास :

उद्योग : सालों के शोध और विकास के दम पर आई टी सी ने कई-कई किस्मों के तैल-बीजों के न और विकास का भी सूत्रपात किया है, जिससे आयात की मात्रा कम होगी और हजारों-हजार नों के फलने-फूलने में मदद मिलेगी ।

ार कल्याण : अपनी विस्तृत वितरण व्यवस्था द्वारा आई टी सी परिवार-नियोजन के साधन लों से उपलब्ध कराते हुए गांव-कस्बों तक में छोटे परिवार और कई साल के अन्तर में न-प्राप्ति के लाभ का प्रचार-प्रसार कर रही है ।

-उद्योग : शाहजहांपुर में आई टी सी ने त्रिवेणी हैंडलूम्स के ज़रिए कालीन-बुनाइ उद्योग को जीवित किया ताकि २५०० से भी ज्यादा परिवार बेहतर कमा सकें, बेहतर जीवन जी सकें। कालीन न द्वारा आई टी सी विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर रही है ।

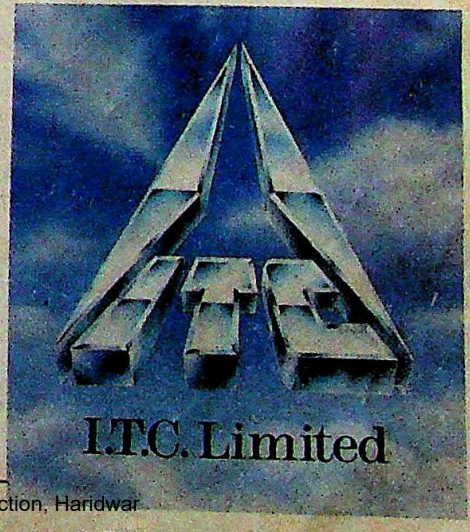

Contract. ITC. 78.88 HIN

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

नई दिशाएँ, नई आशाएँ

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

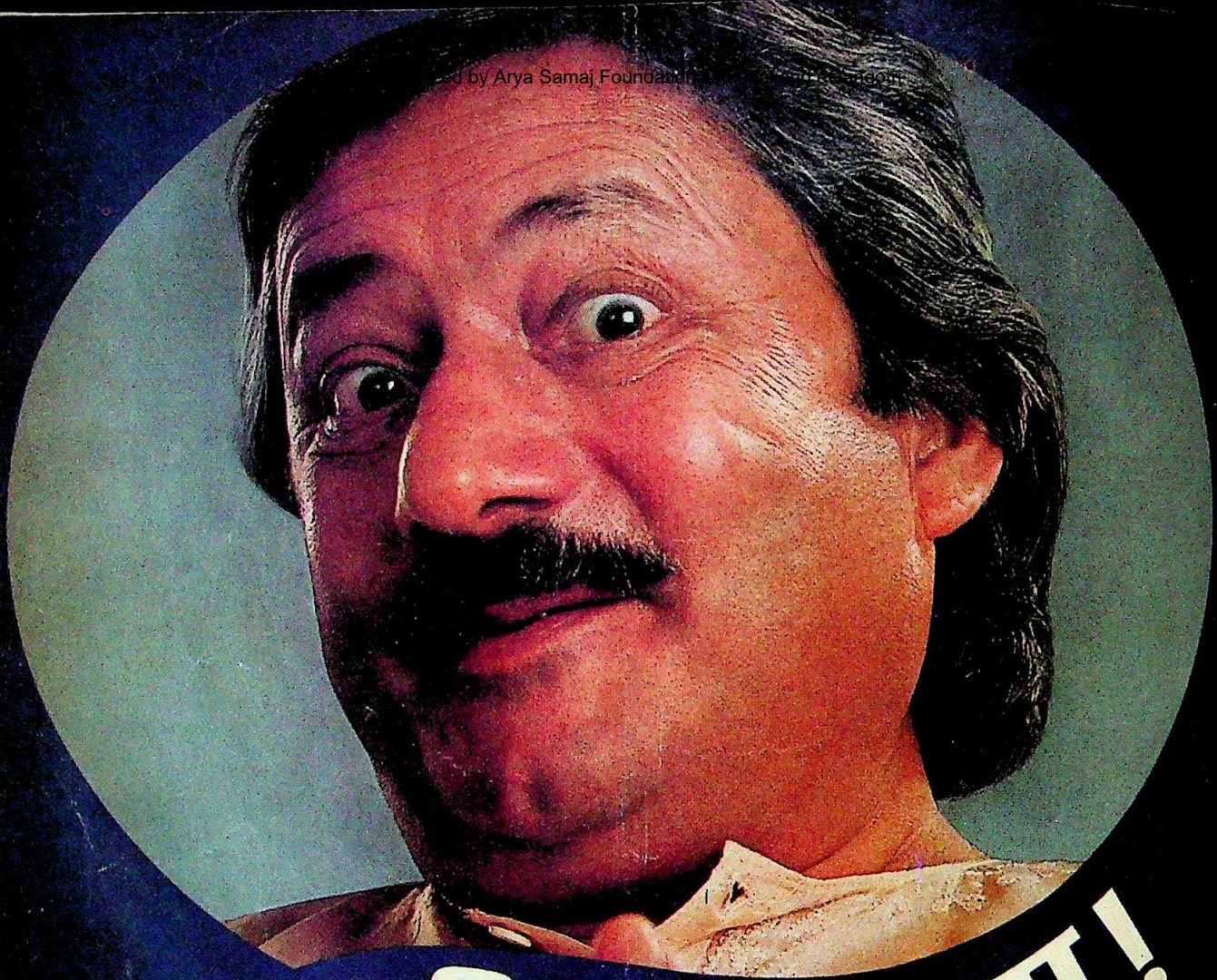

मस्ती का आलम!

जी हां, आपका मनपसन्द पान पराग उच्च क्वालिटी एवं अनूठी सुगंध वाले ज़र्दे से युक्त भी उपलब्ध है! इसका अनुपम स्वाद ज्यादा देर तक रहता है!

कभी भी, कहीं भी, बस अपना पाउच खोलिए तथा दिलकश स्वाद का आनन्द लीजिए!

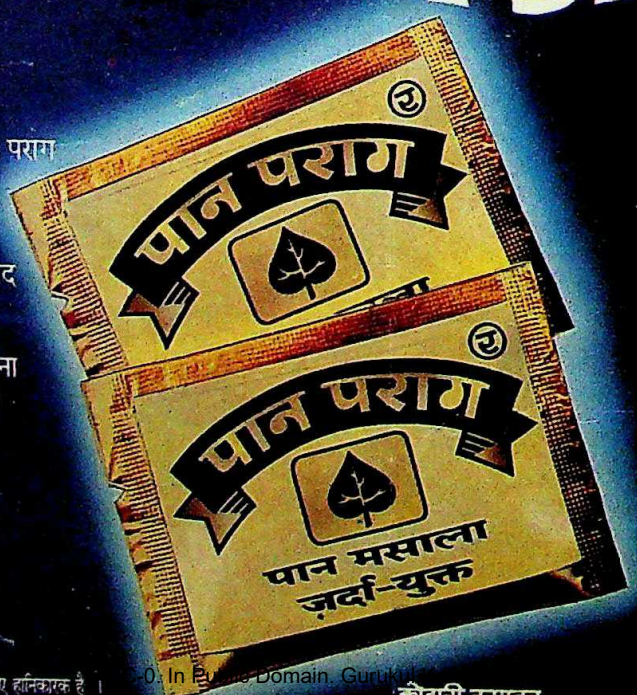

पान पराग
ज़र्दा-युक्त

वैधानिक चेतावनी : तम्बाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul

कोठारी उत्पादन

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इंडिया टुडे
संपूर्ण समाचार पत्रिका
वर्ष 2, अंक 14 16-31 मई, 1988

प्रधान संपादक: अरुण पुरी
वरिष्ठ संपादक: प्रभु चावला

लिविंग मीडिया इंडिया प्रा. लि., एफ-14, कंपिटेंट हाउस, कनाट प्लेस, नई दिल्ली के लिए अरुण पुरी द्वारा संपादित और प्रकाशित तथा थॉमसन प्रेस इंडिया लि. फरीदाबाद, हरियाणा में मुद्रित.

संपादकीय कार्यालय:
लिविंग मीडिया इंडिया प्रा. लि., एफ-14/15, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001. फोन: 331 5801-4. टेलेक्स: 31-61245 INTO IN, तार: लिवमीडिया नई दिल्ली.

मुख्य सर्कुलेशन कार्यालय:
इंडिया टुडे सर्कुलेशन मैनेजर, एफ-14, कंपिटेंट हाउस, कनांट प्लेस, मिडल सर्कल, नई दिल्ली-110001. फोन: 3313076-8, टेलेक्स: 31-62634 INTO IN, तार: सर्कुलेट, नई दिल्ली.

मुख्य विज्ञापन कार्यालय:
28 ए और बी, जॉली मेकर चैंबर-2, नरीमन पाइंट, बंबई-400021. फोन: 2026152, 2029326, 2029435, टेलेक्स: 11-5373 THOM IN, तार: लिवमीडिया बंबई.

क्षेत्रीय विज्ञापन कार्यालय:
के-9, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001, फोन: 3325378, 3323576, 3321323, 3321273; टेलेक्स: 31-62124 THOM IN, तार: लिवमीडिया, नई दिल्ली; फागुन चैंबर्स, 26 कमांडर-इन-चीफ रोड, मद्रास-600105. फोन: 477188, 477770, टेलेक्स: 041-6177 INTO IN, तार: लिवमीडिया, मद्रास; 74/1, मेट मार्क्स रोड, बंगलूर-560001. फोन: 568448, 579037, 579089. टेलेक्स: 0845-2217 INTO IN, तार: लिवमीडिया, बंगलूर; 12-सी, एक्सप्रेस 46-सी, चौरंगी रोड, कलकत्ता-700016 फोन: 445398, 447726, टेलेक्स: 021-3138 INTO IN, तार: लिवइन-मीडिया, कलकत्ता.

कॉपीराइट 1984 लिविंग मीडिया इंडिया प्रा. लि. विश्व भर में सर्वाधिकार सुरक्षित. किसी भी रूप में सामग्री की नकल प्रतिबंधित. इंडिया टुडे अनिमंत्रित प्रकाशन सामग्री को लौटाने की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता.

नेपाल में 6 रुपए

दिलचस्प ब्यौरा

आवरण कथा 'विवादों की विरासत' (15 मई) में जनरल के. सुंदरजी के व्यक्तित्व और कार्य-प्रणाली का रोचक विवरण पढ़ने को मिला. भले ही उनका कार्यकाल विवादास्पद रहा हो, इसमें संदेह नहीं कि सेना के आधुनिकीकरण, नई दृष्टि और परिवर्तन के लिए वे याद किए जाते रहेंगे.
—सुजीत कुमार, दिल्ली

■ लीक से हटकर कदम उठाने वाले व्यक्ति को हमेशा ही संदेह की नजर से देखा जाता रहा है: सुंदरजी भी इसके अपवाद नहीं. ऑपरेशन ब्रासटैक्स की असफलता और कतिपय आलोचनाओं के बावजूद उन्हें सेना में उच्च तकनीक को प्रोत्साहन देने और पारंपरिक ढांचे में परिवर्तन लाने का श्रेय तो देना ही पड़ेगा.
—रामदास भारद्वाज, ऊना (हि.प्र.)

■ खुद सुंदरजी के शब्दों में चूंकि 'बदलाव असुविधाजनक ही होता है' इसीलिए परिवर्तन के लिए उठाए गए कदम 'विवादों की विरासत' बना दिए गए हैं. अन्यथा रणनीतिक विचारदृष्टि, आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा के धनी के. सुंदरजी दूसरे सेनाध्यक्षों से ज्यादा सक्रिय रहे हैं.
—अजय माथुर, सुजानगढ़ (राज.)

खोखलापन उजागर

कसौटी के अंतर्गत 'तहकीकात नहीं तमाशा' (15 मई) में सरकारी 'जांच' एजेंसियों और समितियों के खोखलेपन को आपने बखूबी उजागर किया है. अब तक बिठाई गई जांच समितियों में से एक ने भी सच को उजागर कर निष्पक्ष रिपोर्ट तैयार करने का साहस नहीं किया है. सभी जानते हैं कि इनका एकमात्र उद्देश्य सरकार को निर्दोष साबित करना और लोकतांत्रिक परंपराओं की औपचारिकता निभाना ही होता है.
—ललिता झा, दिल्ली

फिर वही लटके

विशेष लेख 'नेता के आगे नतमस्तक' (15 मई) से साफ जाहिर है कि हाथ से निकल चुकी सत्ता को फिर हथियाने की तैयारी इंका ने अभी से शुरू कर दी है. राजीव का एमजीआर द्वारा मुफ्त भोजन वितरण की योजनाओं को जारी रखना क्या इस बात का सबूत नहीं कि लोकप्रिय होने के लिए वे खुद भी वही लटके अपनाना चाहते हैं, भले ही वे विपक्षी राज्य सरकारों की इसके लिए आलोचना करते आए हैं. —देवेंद्र अरोड़ा, फरीदाबाद (हरियाणा)

सराहनीय कदम

'आजकल' के अंतर्गत 'हवाखोरी, बंद' (15 मई) पढ़ा. सरकारी विमानों के व्यक्तिगत उपयोग पर पाबंदी लगाकर निश्चय ही भागवत झा आजाद ने एक सराहनीय कदम उठाया है. इससे बचत तो खैर होगी ही, सरकारी साधनों के मनमाने उपयोग की परंपरा पर भी अंकुश लगेगा.
—अप्पू कुमार, मोतिहारी (बिहार)

प्रेरणास्रोत

'खुदाई खिदमतगार' (15 मई) पढ़कर सुखद आश्चर्य हुआ कि निःस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने वाले डॉ. मोदी जैसे लोग अभी मौजूद हैं. अंधाधुंध पैसा कमाने वाले निजी डॉक्टर और लापरवाही से मरीजों की जान से खेलने वाले सरकारी डॉक्टर क्या डॉ. मोदी से कोई प्रेरणा लेंगे?
—सुखविंदर सराफ, दिल्ली

महत्वपूर्ण योगदान

'उगते सूरज के देश में सांस्कृतिक चकाचौंध' (15 मई) के अंतर्गत जापान में भारत महोत्सव की रोचक जानकारी मिली. इन आयोजनों के लिए भले ही सरकार की आलोचना की जाती हो लेकिन यह सच है कि विदेशों में भारत की छवि निखारने और भारत की गौरवशाली संस्कृति को लोकप्रिय बनाने में इन उत्सवों ने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है.
—अजय शर्मा, लुधियाना (पंजाब)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अविश्वसनीय निष्कर्ष

आवरण कथा 'उलझनों में उलझा सच' (30 अप्रैल) बोफोर्स प्रकरण की तमाम पेचीदगियों, रहस्यों तथा परदे के पीछे चलने वाली राजनीति से जुड़े हुए अनेक अहम सवालों का खुलासा है. संयुक्त संसदीय जांच समिति की पूरी प्रक्रिया से स्पष्ट हो गया है कि उसकी भूमिका भ्रामक तथ्यों की तकनीकी मीमांसा करना मात्र है. वरना बोफोर्स के पूर्व अधिकारी मार्टिन आर्दबो तथा विश्वविख्यात शस्त्र व्यापारी अदनान खाशोगी को क्यों नहीं तलब किया गया. उनकी गवाही से अनेक महत्वपूर्ण तथ्य उद्घाटित हो सकते थे.

—**शिवपूजन तिवारी,** उन्नाव (उ.प्र.)

■ वातावरण में फैले धुएं को देखकर लगता है कि आग की खबर सच है. पर आग लगाने वाले गुप्त हाथों तक पहुंचना इतना सरल नहीं है. जब पत्र-पत्रिकाएं जांच समिति से दो कदम आगे चल रही हों, समिति से लोगों की विश्वसनीयता उठ जाना स्वाभाविक ही है.

—**गीता मल्होत्रा,** नई दिल्ली

■ बोफोर्स विवाद भारतीय रक्षा व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था और मंत्रिमंडल की नैतिकता पर एक गंभीर प्रश्नचिन्ह बनकर खड़ा है. सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग कर नाम मात्र की बनी संयुक्त संसदीय समिति द्वारा सरकार भले ही इस मामले में अपनी छवि को साफ घोषित कर ले पर जनता भी बेवकूफ नहीं है.

—**संजय कुमार,** पटना (बिहार)

■ शंकरानंद समिति ने सबूतों के साथ जैसा खिलवाड़ किया वह साफ तौर पर दलालों को शह देना ही है. राजीव द्वारा ऐसी जांच समितियां गठित करने का मकसद खुद अपने और अपने दोस्तों पर लगी कालिख को मिटाना ही था. राजीव के ऐसे कार्यकलापों की वजह से वे देश के सामने और भी संदेहास्पद बनते जा रहे हैं.

—**भोलानाथ गुप्त,** लिलुआ (प. बंगाल)

■ शंकरानंद और उनके सहयोगियों ने अपने आका को एक बड़े संकट से बचा लिया है. यदि शुरू से ही विपक्ष की बात मानकर तटस्थ समिति बनाई जाती तो आज भारतीय राजनीति का नक्शा कुछ और होता.

—**संजय रांका,** सैलाना (म.प्र.)

■ संसदीय समिति को अपना काम करने के लिए पूरे दस्तावेज उपलब्ध क्यों नहीं कराए गए? सभी गवाहों की सूचना उसे समय पर क्यों नहीं दी गई? ये सवाल सरकार की कार्यशैली पर प्रश्नचिन्ह लगाते हैं.

—**संतोष कुमार कुदेशिया,** मैनपुरी (उ.प्र.)

■ संसदीय समिति द्वारा की गई लीपापोती इस धारणा को मजबूती ही प्रदान करती है कि सरकारी जांच आयोग का कार्य गड़े मुर्दे उखाड़कर सारे तामझाम के साथ कफन पहना पुनः दफना देना भर होता है.

—**शैलेश कुमार सिंह,** सिदरी (बिहार)

■ आखिर इस विवाद में कुछ तो सचाई होगी ही अन्यथा एक वर्ष से यों ही चर्चित न रहता और न ही इतनी राजनैतिक उथल-पुथल होती. बोफोर्स जांच समिति के निर्णय के अंतिम समय ही स्वीडिश रेडियो द्वारा जारी की गई नई सूचना से निश्चय ही विवाद बढ़ाने की ऊर्जा मिल गई है. इससे संदेहों का जाल और गहराया है.

—**राजीव कुमार सचान,** इलाहाबाद (उ.प्र.)

मजबूर मतदाता

कसौटी में 'एकता का छलावा' (30 अप्रैल) पढ़ा. विपक्षी नेताओं की कलाबाजियां देख उनकी बुद्धि पर तरस आता है. विपक्षी एकता की हास्यास्पद स्थिति देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है. सशक्त विकल्प के अभाव में पुनः इंका की सरकार बनना तय है, चाहे मतदाता उसे नापसंद ही क्यों न करते हों?

—**मरत पी. बुद्धदेव,** सेंधवा (म.प्र.)

■ वस्तुतः विपक्ष में एकता का सदा ही अभाव रहता आया है और यही कारण है कि सिर्फ 30 प्रतिशत मत प्राप्त कर कांग्रेस सत्ता बनाए रखती है. विपक्ष की एकता जितनी आवश्यक है, उतनी ही असंभव भी प्रतीत होती है.

—**विश्वजीत झा,** दिल्ली

■ वास्तव में चुनाव निकट आने पर ही देश का विपक्ष सक्रिय होता है. सत्ता की भागीदारी के लिए बेचैनी किसी एक पार्टी, एक विचार या एक झंडे का निर्माण नहीं कर सकती. किसी भी व्यवस्था को बदलने के लिए महत्वाकांक्षा नहीं, त्याग की भी जरूरत होती है. दुर्भाग्यवश विपक्षी पार्टियां इसी त्याग की मानसिकता का विकास नहीं कर पाई हैं.

—**राजीव लोचन मंटू,** घोसैठ (बिहार)

■ जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए विपक्ष को अपना रवैया बदलना होगा, वरना विपक्ष के प्रति आक्रोश और असंतोष तो बढ़ेगा ही, साथ ही देश को अंधकार की ओर ले जा रही इंका सरकार के हाथ भी मजबूत होंगे.

—**तारकेश कुमार ओझा,** खड़गपुर (प. बंगाल)

सपना है एकता

विशेष लेख 'सच और सपने का फर्क' (30 अप्रैल) पढ़ा. देश में विपक्ष की एकता सचमुच एक सपना मात्र है क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां एकता के प्रयास कर रही हैं उनमें स्वयं ही एकता नहीं है. जनता पार्टी आंतरिक कलह से त्रस्त है. लोकदल (ब) के नेता देवीलाल खुद को प्रधानमंत्री से कम नहीं समझते. दूसरों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले रामराव खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हैं. जनमोर्चा किधर जाए वाली स्थिति में है. ऐसी हालत में विपक्ष की एकता कैसे संभव है.

—**किशनसिंह पंवार,** महूगांव (म.प्र.)

■ लेख पढ़कर लगा कि विपक्षी एकता के प्रयास पानी के उस बुलबुले के समान हैं, जो जितनी जल्दी बनता है उतनी ही तेजी से फूट जाता है. इस समय भारत की जनता एक मजबूत विपक्ष का स्वागत करने के लिए तैयार है पर अफसोस यही है कि कुछ विपक्षी नेता अपने स्वार्थों के लिए विपक्षी एकता के प्रयासों में रुकावट पैदा कर रहे हैं.

—**राकेश धावरी,** सिरसा (हरियाणा)

■ भारत में विपक्षी नेता कभी भी जनता की मनःस्थिति भांपकर एक नहीं हो पाएंगे. विपक्षी नेताओं की पदलोलुपता व एक-दूसरे की टांग खींचने की प्रवृत्ति यदि जनता में उनकी रही-सही विश्वसनीयता भी खत्म कर दे तो कोई आश्चर्य नहीं.

—**योगेंद्र राठौड़,** जयपुर (राज.)

■ अफसोस है कि मौजूदा शासन को बुरा भला कहने और सारे विपक्ष को एक सूत्र में बांधकर राजीव सरकार को गिराने की कसम खाने वाले लाख कोशिशों के बावजूद एक नहीं हो सके. ऐसे में ये क्या राजीव सरकार को गिराएंगे.

—**ठाकुर रंजीत सिंह,** बंबई (महाराष्ट्र)

नकारात्मक रवैया

'विकल्प तलाशने का वक्त' (30 अप्रैल)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सरताजों में सरताज

एक्साइड एम एक्स मोटरसाइकल व स्कूटर बैट्री

एक्साइड एम एक्स—तकनोलोजी का नन्हा-सा कमाल। जापानी और अन्तर्राष्ट्रीय मानदंड के अनुकूल। क्लोराइड के शोध द्वारा खास भारतीय वातावरण और आजकल की ईंधन-सक्षम वाहनों के लिये सर्वोत्तम बनायी गयी।

एक साल की गारंटी और देश भर में फैले हुए विशालतम एक्साइड डीलर समूह का समर्थन भी।

एक्साइड एम एक्स पहुँचाती है आप तक एक्साइड के अनोखे फायदे—बैट्री संग आपको मिलती है सम्पूर्ण विश्वसनीयता, निर्भरता और निरन्तर सेवा की सुविधाए।

एक्साइड एम एक्स रेंज

6 MX 4-2A	इंड सुज़ुकी, यामाहा १००
12 MX 2.5 L-C	हीरो होंडा
12 MX 5 L-B	काइनेटिक होंडा, बजाज कावासाकी
12 MX 5.5	यामाहा ३५०, एनफील्ड सुपरस्टार

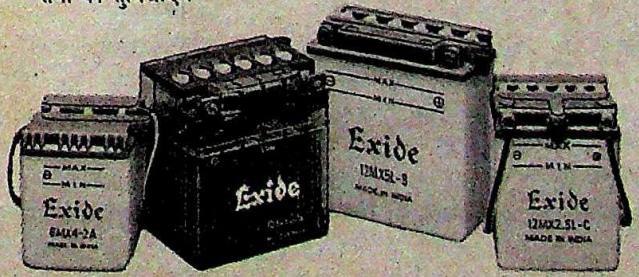

एक्साइड चलती रहे हर दम... चाहे बाकी जायें थम

क्लोराइड इंडिया का उत्पादन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Artig510

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पढ़ा. लेख ने सरकार के नकारात्मक रवैये को स्पष्ट कर दिया. सरकार जितना नरम रुख अपना रही है आतंकवादी उतने ही सिर चढ़ रहे हैं. इस समस्या का खास पहलू यह है कि पंजाब के अधिकारी आतंकवादियों पर हाथ डालना उचित नहीं समझते क्योंकि वे जानते हैं कि सरकार न जाने कब आतंकवादियों से समझौता कर बैठे और वे न घर के रहें न घाट के.

—**हर्ष कुमार,** मुजफ्फरनगर (उ.प्र.)

■ आखिर कब जागेगी हमारी सरकार? बार-बार विदेशी शक्ति का हाथ होने का दावा करने से पहले क्या सरकार को आतंक की उन वारदातों को बंद करने के लिए कदम नहीं उठाना चाहिए जिनके कारण राज्य के निवासियों, विशेषकर सिखों में असंतोष फैलने लगा है और वे राज्य पुलिस और उनकी 'सुरक्षा' के लिए तैनात सीआरपीएफ आदि से भी भयभीत रहने लगे हैं.

—**नीना अरोड़ा,** चंडीगढ़

■ पंजाब समस्या के हल के लिए सरकार को स्पष्ट नीति के अंतर्गत काम करना चाहिए वरना दो नावों पर पैर रखकर वह स्वयं तो डूबेगी ही, पंजाब को भी ले डूबेगी.

—**अश्विनी सैनी,** मोदीनगर (उ.प्र.)

■ पंजाब में हर मानव दुखी है. अधिकारी आतंकवाद को कुचलने के जितने बयान देते हैं उतनी ही अधिक हत्याएं हो रही हैं. यह वक्त बयानबाजी को छोड़कर राज्य में कुछ कर गुजरने का है.

—**चंदूलाल चांदोरा,** ऐलनाबाद (हरियाणा)

■ सुशील मुनि के तमाम प्रयासों के बावजूद पंजाब आज भी अशांत है और आतंकवादियों के चंगुल में बुरी तरह छटपटा रहा है. विजय का सेहरा उनके सिर पर तभी बंधेगा जब वे दूसरी संस्थाओं के संयुक्त प्रयासों से पंजाब में शांति स्थापित करने में सक्षम होंगे. सुलगते पंजाब को भाषणों की नहीं, शांति के ठोस प्रस्तावों की जरूरत है.

—**सीताराम सिंह पंकज,** सरायरंजन (बिहार)

कर्तव्यनिष्ठा का फल

'सीधे मुकाबले में मात' (30 अप्रैल) में पढ़ा कि किस तरह एक साहसी, कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी को एक आरोपी को हथकड़ी पहनाने के कारण सख्त तहकीकात का सामना करना पड़ा. यह शर्म की बात है कि सरकार भी उन कानूनी कारिंदों के आगे झुक गई जो अन्याय के रास्ते पर थे.

—**बाबू घनश्याम जोशी,** तेजरासर (राज.)

■ आज पुलिस की जो आततायी छवि आम जनता के मन में है उसमें दो राय नहीं. मगर जब कोई पुलिस अधिकारी जीवट से कार्य करता है तो उसके लिए साजिशें रची जाती हैं. कार मालिकों के लिए उनका 'क्रेन बेदी' का रूप हो या हठीले वकीलों को वे 'डंडा बेदी' नजर आती हों, आम आदमी के लिए किरण बेदी 'जीवट बेदी' के रूप में ही उभर कर आई हैं.

—**अनमोल सुरोलिया,** रतलाम (म.प्र.)

■ किरण बेदी का तबादला किसी भी तरह न्यायोचित नहीं है. बेदी ने तो एक आरोपी को ही दंड दिया था. पर जब पुलिस वाले निर्दोष जनता पर अत्याचार करते हैं, तब वकीलों का यह बुद्धिजीवी वर्ग कहां चला जाता है? —**नवीन गोयल,** फतेहाबाद (हरियाणा)

बहादुर की बहादुरी

'नकली पदयात्रा' (30 अप्रैल) पढ़कर लगा मानो बीरबहादुर वाकई बहादुर होते जा रहे हैं. वे पदयात्रा तो क्या सिर के बल चलकर भी यात्रा कर सकते हैं. वी.पी. सिंह अगर यह घोषणा कर देते कि वे उ.प्र. के किसी क्षेत्र की यात्रा नहीं करेंगे तो बीरबहादुर की चिंता समाप्त हो जाती और वे लखनऊ के अलावा सिर्फ दिल्ली ही जाते.

—**दिनेश सिंह 'पाहा',** बरौनी (बिहार)

■ बीरबहादुर का एक सूत्री कार्यक्रम है विश्वनाथ प्रताप को इलाहाबाद में हराना. अगर मुख्यमंत्री जनता के दुख-दर्द के लिए पदयात्रा कर रहे होते तो प्रदेश के और भी जिले हैं जो बहुत पिछड़े हुए हैं.

—**हुकम सिंह कुंवर,** हलद्वानी (उ.प्र.)

शांति खटाई में

'अमन की जद्दोजहद' (30 अप्रैल) में अफगानिस्तान की स्थिति का एक सही आकलन प्रस्तुत किया गया है. जेनेवा वार्ता में शुरू से ही कुछ विसंगतियां रही हैं जिनसे अफगानिस्तान में शांति की संभावना संदिग्ध दिखाई दे रही है. मसलन, अभी तक अंतरिम सरकार के स्वरूप का निर्धारण नहीं हो पाना और रूस द्वारा नजीब सरकार को तथा अमेरिका द्वारा विद्रोही मुजाहिदीन छापामारों को समर्थन देते रहना.

—**प्रणय कुमार मिश्र,** जमालपुर (बिहार)

सरकारी खीझ

'जबरन दागने की कोशिश' (30 अप्रैल) पढ़कर दंग रह गया. चेकोस्लोवाकियाई पिस्तौलों का रुख जबरन अरुण नेहरू की ओर करके सरकार ने अपने ताबूत में एक कील और ठोंकी है. यह आरोप सरकार की खीझ ही दर्शाता है.

—**दुर्गेशनंदन सिंह,** बेगूसराय, (बिहार)

मन भी साफ हो

'देशीपन का चढ़ता बुखार' (30 अप्रैल) पढ़ा. अच्छा है कि नई पीढ़ी अपनी संस्कृति की महत्ता पहचानने लगी है. नई पीढ़ी जिस तरह पश्चिमी सभ्यता को तन से उतार रही है काश उसी तरह दिल से भी उतार फेंके.

—**गुलाम मोहिउद्दीन,** सीतापुर (उ.प्र.)

■ खादी, हस्तशिल्प, स्वदेशी चीजों का बाजार गरमाया, यह सुखद आश्चर्य है. इससे इन छोटे उद्योगों को फलने-फूलने का मौका तो मिलेगा.

—**रमेश कुमार साहू,** पानीतोला (असम)

सस्ती लोकप्रियता

'यक्ष प्रश्न अनुत्तरित' (30 अप्रैल) पढ़ने से लगता है कि धर्मगुरु भी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने में पीछे नहीं. विश्व शांति महायज्ञ कराने वाले पुरी के शंकराचार्य को सती प्रथा को महिमामंडित करने वाले बयान देना शोभा नहीं देता. जिस मां ने उन्हें जन्म दिया है उसी को अग्नि की भेंट करना कहां की बुद्धिमानी है? —**विनोदचंद्र गोयल,** इलाहाबाद (उ.प्र.)

■ आज नारी पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बाकायदा देश की उन्नति में पूरा योगदान दे रही है. ऐसे में यदि शंकराचार्य जैसे लोग सती प्रथा जैसी बुराई का समर्थन करें तो उनको अवश्य ही दंड देना चाहिए ताकि भविष्य में कोई व्यक्ति ऐसी कुप्रथाओं के हक में बोलने का साहस न कर सके.

—**संजीव आर्य,** दिल्ली

■ पुरा महादेव में दोनों धर्म विशेषज्ञों का शास्त्रार्थ टालकर सरकार ने ठीक ही किया. व्यर्थ ही वाद-विवाद बढ़ता. आश्चर्य है कि धर्मगुरु आज की ज्वलंत समस्याओं से जूझने के लिए पदयात्राएं, जनजागरण अभियान क्यों नहीं शुरू करते.

—**श्याम मनोहर व्यास,** उदयपुर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कसौटी

दिग्भ्रमित दृष्टि

"मौजूदा सरकार की विदेश नीति की हालत कुल मिलाकर इठलाती चाल में चलने वाली उस मुर्गी जैसी है जो यह नहीं समझ पा रही कि अंडे कहां दे. 'सही गुटनिरपेक्षता' के तकाजे पर कभी तो सरकार अमेरिका को गले लगाने की कोशिश करती है और फिर कभी सचमुच 'गुटनिरपेक्ष देश दिखने' के लिए वह मॉस्को की ओर कदम बढ़ा देती है..."

अनुभवी राजनयिक त्रिलोकीनाथ कौल ने भारतीय विदेश नीति के बारे में यह टिप्पणी अपनी ताजा पुस्तक *'एंबेसेडर्स नीड नॉट लाई'* में की है. कौल आजकल मॉस्को में भारतीय राजदूत हैं. यह टिप्पणी वैसे तो जनता पार्टी सरकार के बारे में है लेकिन मौजूदा सरकार पर उतनी ही मौजूं दिखती है. अफगान राष्ट्रपति डॉ. एस.एम. नजीबुल्ला के हाल में भारत के दौरे के दौरान सरकार ने अफगानिस्तान के मसले पर जो घालमेल किया उससे तो यही उजागर होता है.

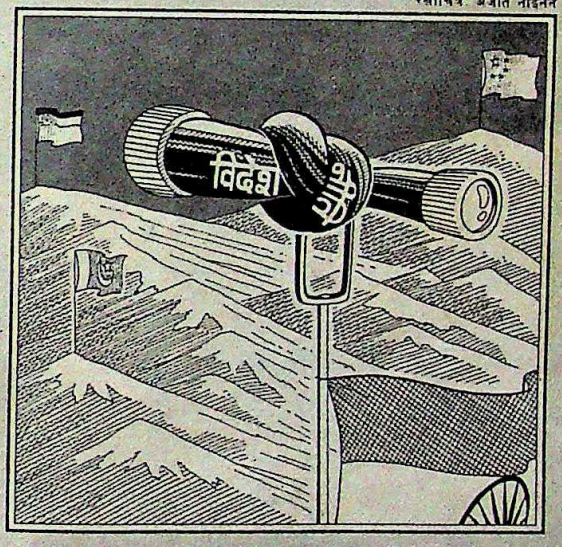

रेखाचित्र: अजीत नाइनन

अफगानिस्तान से रूसी सेनाओं की वापसी के बाद वहां स्थितियां जो मोड़ लेती हैं उसके प्रति भारत का चिंतित होना निस्संदेह स्वाभाविक है. दोनों देशों के बीच दोस्ती की लंबी परंपरा रही है. इसलिए वहां आज अगर कोई कट्टरपंथी शासन स्थापित होता है तो यह भारतीय हितों के लिए नुकसानदेह ही होगा. लेकिन राजीव गांधी की सरकार ने भारतीय हितों का जिस तरह से संरक्षण करने की कोशिश की है उससे दूसरे देश के मामलों में बेमतलब दखलंदाजी की घिसिपुआ कूटनीति का ही परिचय मिलता है.

दिसंबर 1979 में जब रूसी सेनाएं अफगानिस्तान में घुसी थीं तो भारत ने रूस का खुल्लमखुल्ला पक्ष लिया था. इस कारण भारत की साख मुजाहिदीन के बीच तो गिरी ही थी, उसकी गुटनिरपेक्षता की नीति की भी पश्चिमी देशों में बड़ी भद पिटी थी. ऐसे में अफगान मसले के किसी समझौते में अपनी चलाने की हैसियत भारत ने खो दी. लेकिन रूस ने जब वहां से निकलने का इरादा जाहिर किया तो भारतीय विदेश मंत्रालय को भी अपनी गलती का एहसास हुआ. और तब उसने सोच-समझकर कूटनीति चलानी शुरू की—सूचनाओं का आदान-प्रदान और जब जरूरत हो, मध्यस्थता की तैयारी बताना वगैरह.

लेकिन अचानक ही पैंतरा बदल गया. पता नहीं किस काल्पनिक उड़ान में राजीव गांधी ने अफगान मसले पर बातचीत के लिए पाकिस्तानी राष्ट्रपति जिया-उल-हक को निमंत्रण दे दिया. जिया ने इसे तुरत ठुकरा कर भारत को बुरी तरह झटका दिया. इसी तरह उतावलीपन में नजीबुल्ला के दिल्ली दौरे का कार्यक्रम तय किया गया. उतावलीपन का आलम यह था कि भोज वगैरह राजकीय सभारोहों का कार्यक्रम पहले से तय नहीं किया जा सका. प्रधानमंत्री सचिवालय ने नजीबुल्ला को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में औपचारिक भोज का न्यौता दिया. लेकिन नजीबुल्ला ने जब रोज़ादार होने के कारण न्यौता नामंजूर कर दिया तो शर्मिंदगी के मारे सचिवालय ने बाद में इस आयोजन को इफ्तार और रात्रि भोज में तब्दील कर दिया.

दरअसल जितनी तत्परता से नजीबुल्ला को दिल्ली दौरे का न्यौता दिया गया और जिस फुर्ती से इसे मंजूर कर लिया गया उससे तो यही लगा कि यह सब रूस के इशारे पर हुआ.

ऐसे वक्त जबकि भारत और अमेरिका एक-दूसरे के करीब आने की तैयारी में दिख रहे हैं, नजीबुल्ला को न्योत कर भारत ने अमेरिकी प्रशासन को कुछ उलझन में ही डाल दिया है. हल्के लड़ाकू विमान बनाने की भारतीय योजना में सहायता का रक्षा समझौता और फिर क्रे सुपर कंप्यूटर की खरीद का मामला दोनों देशों के संबंधों के सहज होते जाने का ही तो सबूत है. लेकिन अमेरिका नजीबुल्ला के भारतीय दौरे को मौजूदा अफगान सरकार को मान्यता देने की कोशिश मानता है.

अमेरिका मानता है कि नजीबुल्ला सरकार को व्यापक समर्थन नहीं है इसलिए अंतिम समझौते के पहले अंतरिम सरकार का गठन जरूरी है. किसी गैर-कम्युनिस्ट देश ने नजीबुल्ला सरकार को मान्यता नहीं दी है. इसलिए सीधे राष्ट्राध्यक्ष को निमंत्रित करके भारत अफगान मसले के संदर्भ में रूस की उंगली थामे नजर आने लगा है. यही नहीं, उसने अमेरिकी कांग्रेस के उन भारत समर्थकों को भी नाराज कर दिया है जो उच्च तकनीक के हस्तांतरण के सवाल पर कट्टर भारत विरोधियों से लड़ते रहे हैं.

घालमेल का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता. ऐसे वक्त जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच कई अहम मुद्दों पर आपसी समझदारी की बेहद जरूरत थी, भारत की ओर से की गई प्रायः सभी पहल उलझनपूर्ण ही रही है. एक ओर तो नजीबुल्ला को भारत बुला लिया गया, दूसरी ओर विदेश सचिव के.पी.एस. मेनन को इस्लामाबाद भेज दिया गया ताकि दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य हों. पाकिस्तान की मान्यता रही है कि नजीबुल्ला सरकार के रहते पाकिस्तान में टिके अफगान शरणार्थी स्वदेश नहीं लौट पाएंगे. सो उसने नजीबुल्ला की भारत यात्रा की इतनी तीखी भर्त्सना की कि मेनन की मुहिम का मकसद ही जैसे मारा गया.

यहां अहम मुद्दा यह है कि भारत ने अफगान मसले को ऐसे वक्त तुरुप का पत्ता बनाने की कोशिश की है जब वह खुद को क्षेत्रीय महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में लगा है. ऐसे में वह अफगान मसले पर ऐसा रुख अख्तियार करने की छूट नहीं ले सकता जिससे उसकी छवि निर्गुट राष्ट्र के बजाय इस क्षेत्र में रूसी हितों के पोषक की बनती हो.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अगर आप सोचते हैं
कि साधारण बीमा पालिसियां
इस कदर तैयार होते हैं...

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सोचिए नेशनल परिवर्तन के लिए

हम जानते हैं कि आप जिन कठिनाइयों से जूझते हैं वह आपके लिए और आपके पेशे और व्यवसाय के लिए अनोखा है।

इसीलिए आप देखेंगे कि हमारी पालिसियां आपके मनमुताबिक हैं और आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने में हर प्रकार से सक्षम हैं।

हमारी पालिसियां जो सम्भवतः हर क्षति की पूर्ति करने में सक्षम हैं, जैसे मवेशियों से लेकर कम्प्यूटर, कृषि से विमानन तक।

पिछले वर्ष हमने जिन तीन लाख पचास हजार से भी अधिक दावों को निपटाये हैं यह हमारी पालिसियों की विशालता को प्रमाणित करते हैं।

हमारे पेशेवर दल, जैसे वेटनरी सर्जन, कम्प्यूटर एनालिस्ट्स और इंजीनियर आदि हमेशा आला दर्जे की सेवा के लिए तैयार मिलेंगे।

प्रतिदिन हम कदम दर कदम आपके निकट पहुंच रहे हैं क्यों कि हमारे आफिसों का जाल देश में आश्चर्यजनक ढंग से बढ़ रहा है।

इस में कोई आश्चर्य की बात नहीं कि जब भी लोग साधारण बीमा के बारे में विचार करते हैं तो पहले नेशनल के संबंध में ही सोचते हैं। इस का अर्थ है आरंभ से अंत तक उत्तम सेवा।

सोचिए नेशनल बीमा सुरक्षा के लिए

नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

(भारतीय साधारण बीमा निगम की अनुषंगी)

TSAC-NIC-3

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मार्क्सवादी इस्लाम

● हाल ही में अफगान राष्ट्रपति डॉ. एस.एम. नजीबुल्ला जब नई दिल्ली आए तो उनका रवैया उतना अड़ियल नहीं दिखा जितना अक्सर बताया जाता है. सोवियत फौजों की वापसी और उसके बाद कायम होने वाली सरकार के संभावित ढांचे पर उन्होंने दो दिन तक आला स्तर पर जिस तरह की बातचीत की उससे

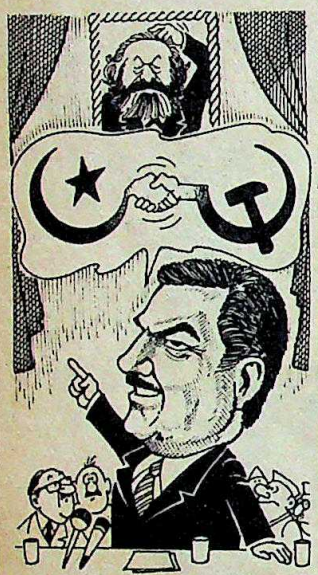

तो यही उजागर होता है. बातचीत की जानकारी रखने वाले साउथ ब्लॉक के सूत्रों के मुताबिक नजीबुल्ला ने इस बात का भी संकेत दिया कि वे निर्वासित बादशाह जहीर शाह के लिए हालांकि गद्दी खाली नहीं करेंगे पर अगर शाह नई सरकार में शामिल हों तो उन्हें कोई एतराज भी नहीं.

भारतीय राजनयिकों और विदेश विभाग के अधिकारियों को इससे इस बात की मोटी-मोटी जानकारी मिल सकी कि अफगानिस्तान में स्थिरता कायम करने के लिए नजीबुल्ला कौन-कौन सी रियायतें देने को तैयार हैं. अफगान राष्ट्रपति इस सलाह से सहमत बताए जाते हैं कि काबुल की भावी सरकार का न सिर्फ व्यापक आधार हो बल्कि उसका ढांचा भी बहुदलीय हो ताकि बहुविध समाज बनने का रास्ता साफ हो सके.

सबसे ज्यादा हैरत तो नजीबुल्ला की इस घोषणा से हुई कि अफगानिस्तान एक मार्क्सवादी राज्य होने के बावजूद इस्लाम का सम्मान करता रहेगा और जब मौलवी मस्जिद के बुर्ज से खुदा के बंदों के लिए अजान देने लगेगा, हंसिए-हथौड़े का दूज के पाक चांद से शायद पहली बार मेल होगा.

मुनाफा खच्चरों से

● रक्षा लेखा नियंत्रक के सुझाव पर वित्त मंत्रालय और सेना मुख्यालय पता नहीं कब से रक्षा खर्च कम करने के बारे में डींगें हांकते आ रहे हैं. पिछले बजट में रक्षा खर्च बहुत ज्यादा था. पर दोनों ही सियाचिन अभियान पर अपना सारा ध्यान केंद्रित किए हुए हैं जो अभी तक दुनिया का सबसे खर्चीला सैनिक अभियान माना जाता है.

इसकी मुख्य वजह यह है कि लगभग पूरा अभियान हवाई मार्ग से चलाया जा रहा है. रोज सैकड़ों विमान और हेलिकॉप्टर वहां सामान तथा लोगों को लाने-ले-जाने और हमलों के लिए उड़ान भरते हैं. रक्षा मंत्रालय के जानकार लोग मानते हैं कि इस खर्च पर अंकुश लगाने के लिए पाकिस्तान का अनुभव काम में लाया जाना चाहिए. अपने तथाकथित इलाके का बचाव कर रही पाकिस्तानी सेना को भी

सभी कार्टून: अजीत नाइनन

यह खर्च वहन करना मुश्किल हो गया था. हारकर उसने यहां सामान लाने-ले-जाने का काम एक पुराने उद्यमी को सौंपा और उसने मुनाफा कमाने के लिए एक बेहतरीन नुस्खा निकाल लिया. इस निजी कंपनी ने सैकड़ों खच्चर खरीदे और उन्हें खाद्य पदार्थ और दूसरा साजो-सामान पहुंचाने के काम में लगा दिया. तुरंत यह बात सामने आई कि यह मेहनती जानवर इस असंभव-सी ऊंचाई पर भी काफी कुशलता से काम करता है. इस व्यापारी और खच्चरों के उसके दस्ते पर भारतीय सेना ने कुछ गोलियां भी बरसाईं पर यह क्रम चलता रहा. वैसे भी बिना जोखिम उठाए मुनाफा मिलता कहां है.

अजीब इत्तफाक

● उपराष्ट्रपति शंकरदयाल शर्मा की खिदमत में प्रधानमंत्री कार्यालय ने अब अपनी जंबो जेट संस्कृति पेश की है. इस संस्कृति के सूत्रधार खुद राजीव गांधी रहे हैं. इसके तहत शर्मा को कैरेबियन देशों के दौरे के लिए एअर इंडिया का 747 जंबो विमान दिया गया. हाल में राज्यसभा में राजीव की मौजूदगी में ही इंका सांसदों ने उपराष्ट्रपति का इस कदर अपमान किया था कि उन्होंने रूआंसे होकर इस्तीफा देने की धमकी भी दे डाली थी.

शर्मा के साथ इस दौरे में अखबारनवीसों और तरह-तरह के सरकारी अफसरों समेत 100 से भी ज्यादा लोगों का भरा-पूरा अमला था. उपराष्ट्रपति की इस यात्रा को चूंकि सद्भावना यात्रा का नाम दिया गया इसलिए 140 कलाकारों का एक दल भी उनके साथ वहां भेजा गया था. उसे एक दिन पहले ही बंबई से हवाई जहाज द्वारा रवाना कर दिया गया था. शायद यह इत्तफाक ही था कि राज्यसभा के सभापति ऐसे समय कैरेबियन देशों की यात्रा पर पहुंचे जब संयुक्त संसदीय समिति की रपट जारी होने के बाद संसद में बोफोर्स मुद्दे पर बहस बहुत ही महत्वपूर्ण दौर में चल रही थी.

खास जलसा, खास मेहमान

● रमजान के दिनों में शाम को इफ्तार के समय खत्म होने वाला दिन भर का रोजा अमूमन पारिवारिक आयोजन होता है. राजधानी में इफ्तार के साथ एक विशिष्ट सामाजिक पक्ष भी जुड़ गया है जिससे अब एक नई परंपरा बनती जा रही है.

मुसलमान नेताओं और उनमें भी ज्यादातर इंका नेताओं ने इस पारिवारिक आयोजन को अब जैसे जलसा-ए-खास में बदल दिया है. वे इस पारिवारिक दावत में मंत्रियों और वरिष्ठ अफसरों को न्यौता देते हैं. पर इफ्तार के लिए जिस विशेष मेहमान को बुलाने की सबसे ज्यादा चाहत है वे खुद प्रधानमंत्री राजीव गांधी हैं. वे इफ्तार की कुछ एक दावतों में शरीक भी हुए हैं. उनके रजामंदी वाले इस रवैये को देखते

हुए इंका सांसदों और नेताओं ने अब अपने मुसलमान सहयोगियों पर निमंत्रण पाने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया है ताकि वे इस मौके पर प्रधानमंत्री से मिल सकें. वरना उनसे मिलना तो मानो पहाड़ लांघना ही होता है.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कोई भी व्यापक तापमान हो, मेरे लिए अनुकूल है।

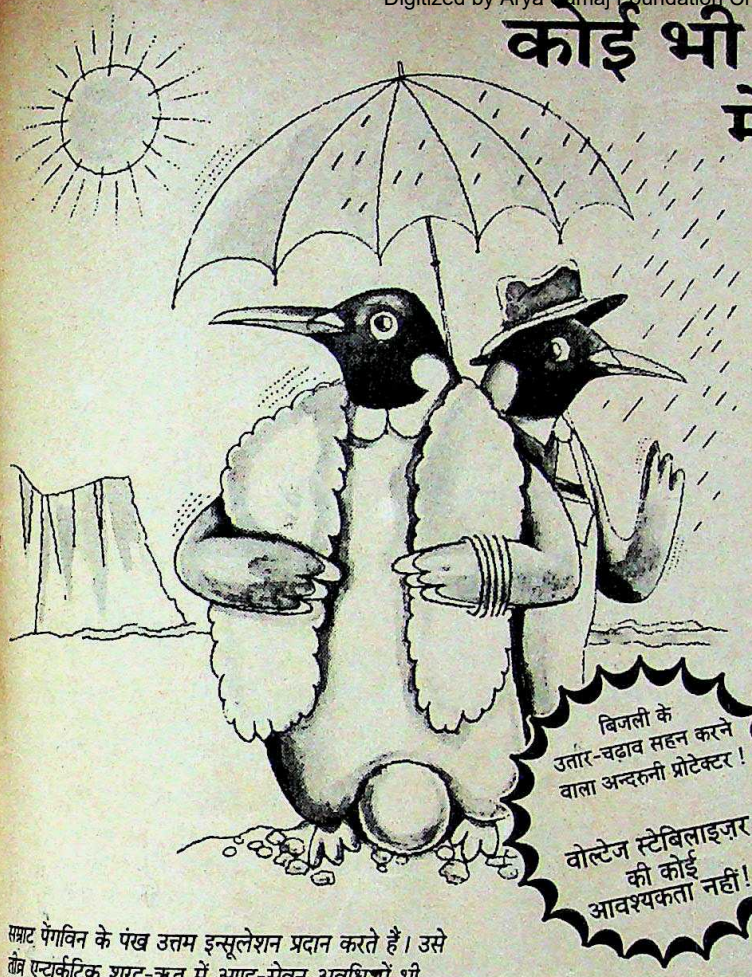

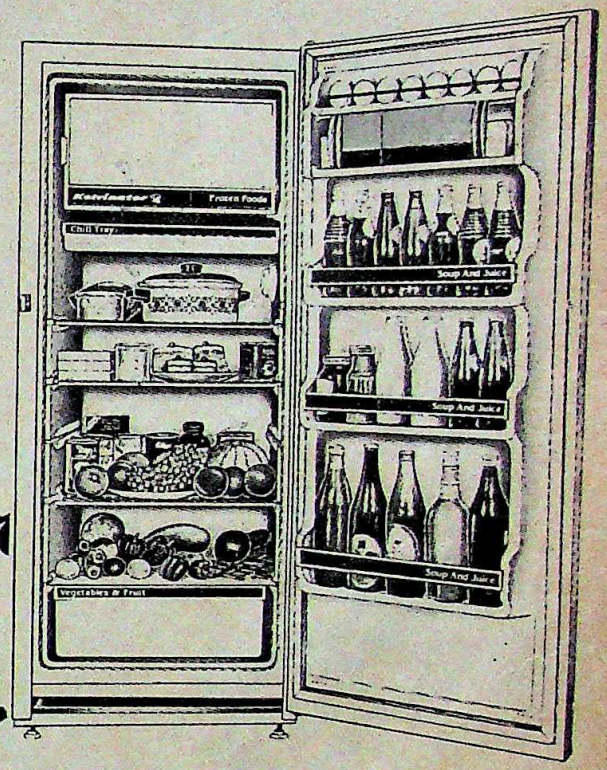

सम्राट पेंगविन के पंख उत्तम इन्सूलेशन प्रदान करते हैं। उसे तीन एन्टार्कटिक शरद्-ऋतु में अण्ड-सेवन अवधि में भी जीवित रहने में सहायता देते हैं।

संदर्भ: रीडर्स डाइजैस्ट की एन्टार्कटिका

केल्विनेटर रेफ़्रिजरेटर कार्यकुशलता का दूसरा नाम। सभी प्रतिकूल परिस्थितियों में इसके ठंडा करने की क्षमता के कारण, यह घर घर में लोकप्रिय है।

इसका श्रेय, इसके विश्वविख्यात "पावर-सेवर" कम्प्रैसर को प्राप्त है। जो उच्च व्यापक तापमान में भी कुशलता से कार्य करता है। शीघ्र ठंडा करता है, उससे भी शीघ्रता से बर्फ़ बनाता है। "पावर-सेवर" कम्प्रैसर, विस्तृत वोल्टेज उतार चढ़ाव सहन करता है तथा इसे वोल्टेज स्टेबिलाइज़र की कोई आवश्यकता नहीं। और फिर यह न्यूनतम बिजली की खपत करता है।

विशेष ख़ूबियां :

* पूर्ण इन्सूलेशन, कैबिनेट तापमान को बेहतर बनाती है।
* मज़बूत ए बी एस लाईनर।
* सर्विस में विश्वसनीय।
* बिजली की खपत में अत्यंत किफ़ायती।
* विशाल स्टोरेज क्षमता।
* टिकाऊ।
* सुन्दर एवं सुदृढ़।
* विभिन्न बाहरी फ़िनिश तथा मनभावन अन्दरूनी रंगों में उपलब्ध।
* अनेक मॉडल।

केल्विनेटर
रेफ़्रिजरेटर
"इसकी ठण्डक...बेमिसाल!"

बिक्री एवं सर्विस के लिए :
एक्सपो मशीनरी लिमिटेड
प्रगति टावर, 26 राजिन्द्रा प्लेस,
नई दिल्ली-110 008

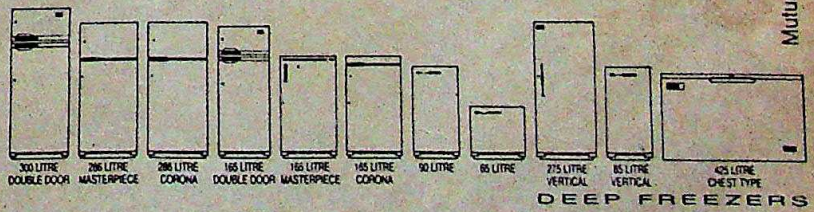

DEEP FREEZERS

Mutual-4510E/HN

केल्विनेटर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारिए

यह कूपन और
आपनी चहेती आवाज़ सुनिए:
बच्चे की खिलखिलाहट

हंसी-खुशी और मौज-मस्ती बच्चों के लिए उतनी ही ज़रुरी हैं जितने ज़रुरी हैं खाना-पीना और हवा. और डिस्नी टुडे लेकर आया है यही मस्ती... यही मज़े.
बस तो फिर यह कूपन भर दीजिए और हर एक को खुश कर दीजिए.

आकर्षक छूट का लाभ उठाईये.

कूपन निम्नलिखित पते पर भेजें:
लिविंग मीडिया इंडिया (प्रा.) लि.
सबस्क्रिपशन डिपार्टमेंट
थॉमसन प्रेस बिल्डिंग .
पो.बॉ. न० 69, दिल्ली-मथुरा रोड
फ़रीदाबाद - 121 007 (फ़रीदाबाद)

मुझे अपने बच्चे के लिए सबस्क्रिपशन चाहिए. यह रहा मेरा सालाना सबस्क्रिपशन ☐ हिंदी रु. 78/- ☐ अंग्रेजी रु. 96/- प्रति के लिए. मैं भुगतान चैक/मनी आर्डर/डिमांड ड्राफ्ट नं. _____ द्वारा कर रहा हूँ.
कृपया प्रति निम्नलिखित नाम व पते पर भेजें:
नाम _____
उम्र _____ लिंग _____
डाक-पता _____
_____
_____
विद्यालय : _____
माता-पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर _____
कृपया भुगतान लिविंग मीडिया इंडिया (प्रा० लि० के नाम पर बनाएं.

Walt Disney's COMICS
डिस्नी टुडे
अब उपलब्ध हर पखवाड़े
हिन्दी और अंग्रेज़ी में

© 1987 THE WALT DISNEY CO., USA.

MILESTONES/DT/114 Hin a

रविशंकर, इंडियन एक्सप्रेस

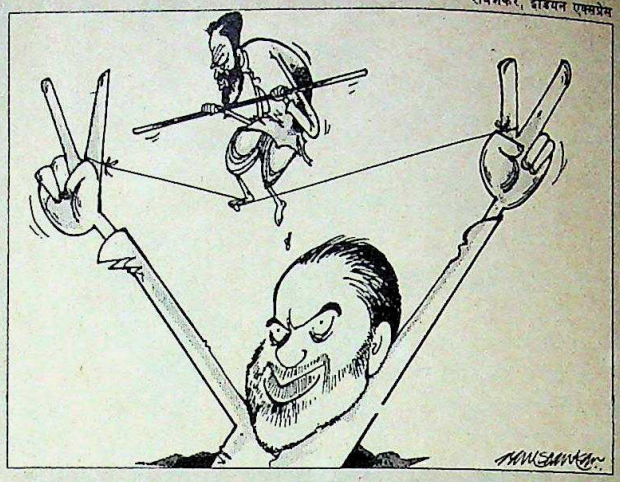

● हालांकि कांग्रेस (इ) की राजनैतिक दल के रूप में कोई अच्छी छवि नहीं है, लेकिन उसमें जनता पार्टी के मुकाबले अनुशासन अधिक है.
■ रामकृष्ण हेगड़े, *आज*

● हां, वह (राजीव गांधी) कान का कच्चा है. क्या करोगे? ■ अरुण नेहरू, *मंडे*

● वामपंथी दल तो (विपक्षी एकता के संदर्भ में) पलायनवादी हैं.
■ मधु दंडवते, *साप्ताहिक हिंदुस्तान*

● भाजपा के बिना केंद्र में कांग्रेस का कोई विकल्प तैयार नहीं हो सकता.
■ अटल बिहारी वाजपेयी, *माया*

● कुछ लोग जैसे नेहरू और इंदिरा जी के साथ बैठकर बड़े हो गए उसी तरह कुछ नेता राजीव गांधी के साथ लगकर 'इमेज' वाले हो गए.
■ हरकिशन लाल भगत, *नई दुनिया*

● दुर्जन और कालाबाजारी करने वाले लोग मेरे पास फटकने की हिम्मत नहीं करते.
■ भागवत झा आजाद, *हिंदुस्तान*

● कुछ अर्थों में सोनिया भारतीय पत्नियों से भी अधिक भारतीय हैं.
■ राजीव गांधी, *राजस्थान पत्रिका*

● भजनलाल दुनिया के सबसे बड़े चोर हैं. ■ देवीलाल, *नई दुनिया*

● मेरा निजी जीवन एमजीआर की मृत्यु के साथ ही खत्म हो गया. इसलिए आज लोगों से छिपाने लायक सचमुच मेरा कोई निजी जीवन नहीं रह गया है.
■ जयललिता, *इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया*

● मैं क्रिकेट ही सोचता हूं, क्रिकेट ही खाता हूं, क्रिकेट ही पीता हूं, क्रिकेट का ही सपना देखता हूं. ■ कृष्णमाचारी श्रीकांत, *स्पोर्टवर्ल्ड*

● कुश्ती संघ में मैं तो सिर्फ शोभा की वस्तु हूं. ■ गुरु हनुमान, *आज*

● मैं आज उस मुकाम पर पहुंच गया हूं जहां मैं खुद को किसी के सामने छोटा या बड़ा नहीं मानता, अमिताभ बच्चन के सामने भी नहीं. ■ मिथुन चक्रवर्ती, *पूर्वी*

● हमारे देश में कुछ लोग बहुत अमीर हैं तो कुछ बहुत ही गरीब. मैं कोशिश करूंगी कि सभी समान हों. ■ श्रीदेवी, *स्टारडस्ट*

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हैलो कहने का नया अन्दाज़

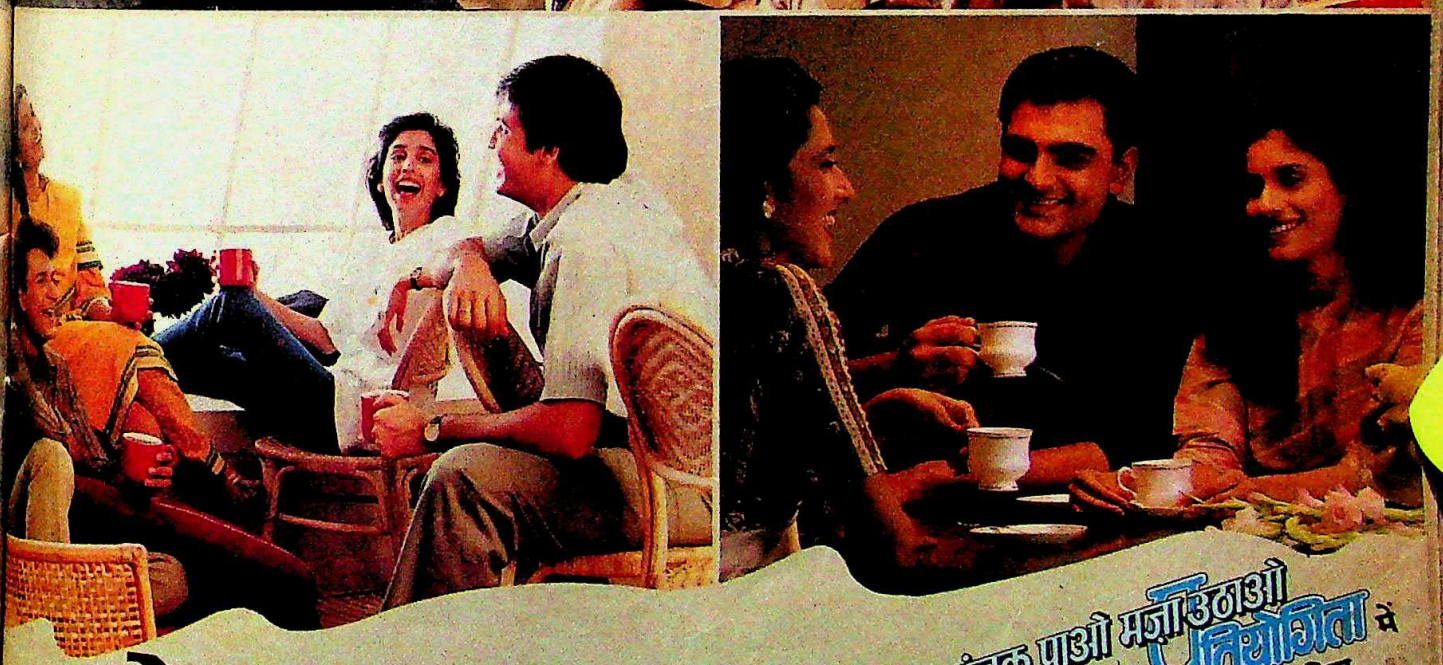

नेस्कैफ़े कॉफी

दुनिया भर की मनपसन्द कॉफ़ी

संग होने की उमंग, जगाए तरंग ऐसे लम्हों में **नस्कैफ़े**.

शत प्रतिशत शुद्ध, ताज़ा कॉफी का आनन्द लीजिए.
नैस्कैफ़े का खास स्वाद-आपके लिए खास तौर से लाए हैं
वो लोग, जिनसे बेहतर कॉफी के बारे में और कोई नहीं जानता.
जब सब संग साथ हो ऐसे लम्हों में-**नैस्कैफ़े**
ऐसा स्वाद जिस पर दुनिया करे नाज़.

संग होने की उमंग

ठंडक पाओ मज़ा उठाओ **प्रतियोगिता** में भाग लीजिए

अपने डीलर से सम्पर्क कीजिए.

TSA/FSL/126/HIN

CC-0. In Public Domain. Gurukul Haridwar

D... ...naj Foundation Chennai and eGangotri

छवि जो दिल में उतर जाये... जे सी टी

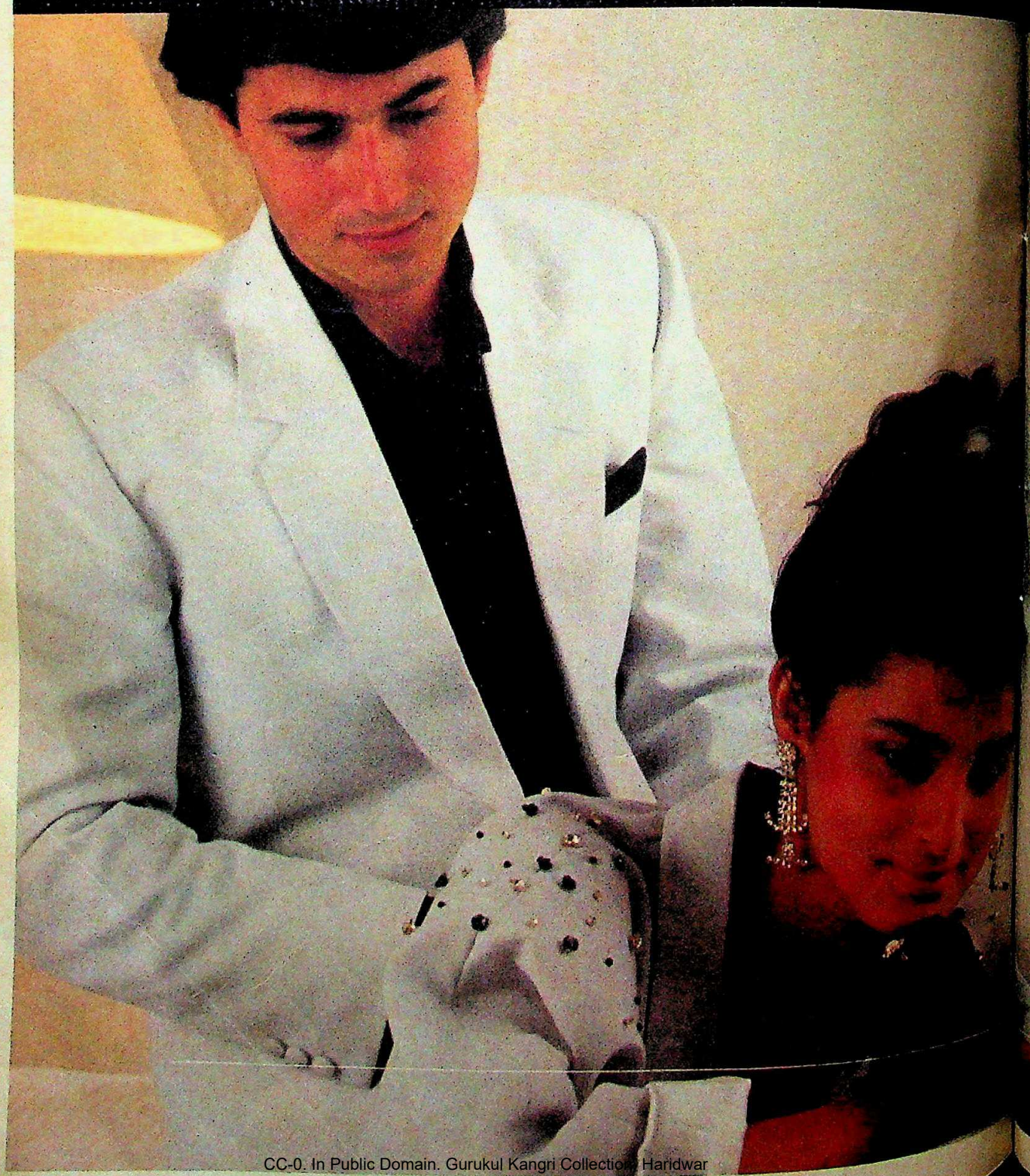

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

The Thapar Group

Phagwara
FABRICS

Contract JCT 20103/88-HIN

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

PHILIPS

फ़िलिप्स

वाह! स्टीरिओ और मोनो टू-इन-वन के क्या-क्या नमूने!
साथ में... ग्राफ़िक ईक्वॅलाइज़र, डबल डैक्स, डिटेचबल स्पीकर्स.
और भी बहुत कुछ. बिना किसी भारी भरकम क़ीमत के!
चाहिए और क्या...!

अब, सारी दुनिया से कहदो
मैंने चाहा फ़िलिप्स
मैंने पाया फ़िलिप्स!

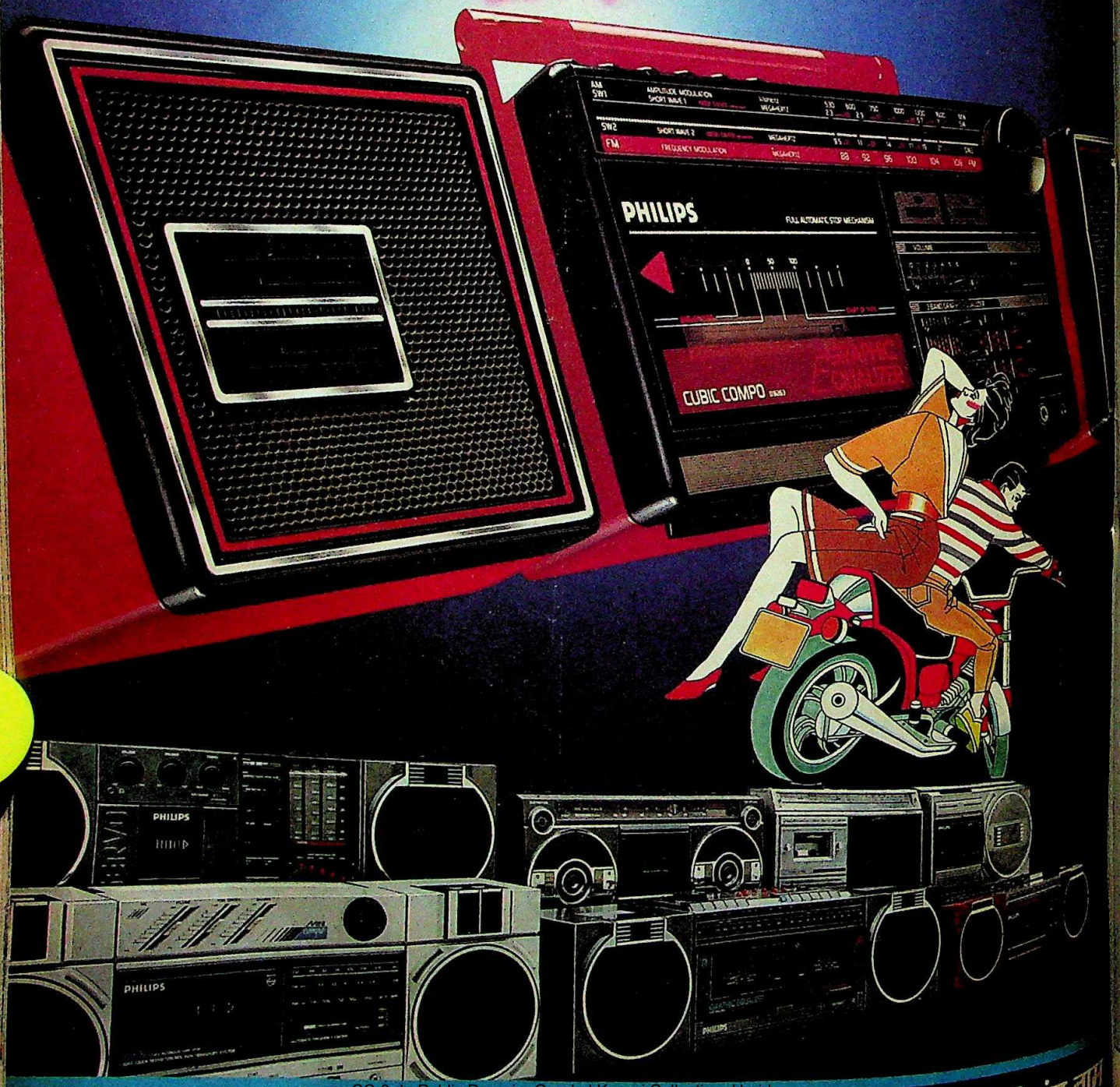

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

फ़िलिप्स-पचास वर्षों से भी अधिक अरसे से भारत के घर-घर में एक भरोसेमंद नाम

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पालतू सदस्य

■ राशन कार्ड पर मिलने वाले सस्ते तेल और चीनी का लालच ऐसा है कि बड़े-बड़े लोग भी इसकी चपेट में आ जाते हैं. खुले बाजार में इन जिंसों की कीमत जितनी ऊंची है उसके मद्देनजर यह लालच बड़ा ही है. यही कारण है कि जाली राशन कार्ड बनवाना या अपने कार्ड में फर्जी सदस्यों के नाम लिखवा देना अब एक राष्ट्रीय मजबूरी का रूप ले चुका है. जितने सदस्य होंगे, राशन भी उतना ही तो मिलेगा! इस तरह की धोखा-धड़ी को पकड़ने के लिए आए दिन राशन विभाग के अधिकारियों को घर-घर जाकर खाक छाननी पड़ती है. खाक छानने के इस अभियान का परिणाम अक्सर यह होता है कि राशन कार्डों में ऐसे सैकड़ों 'भूत-प्रेतों' के नाम पकड़े जाते हैं जिनका असली जिंदगी में कहीं नामोनिशान ही नहीं होता.

सभी कार्टून: अनिल शर्मा

पिछले दिनों राजस्थान के बिजौलिया इलाके में स्थानीय राशन विभाग ने राशन कार्डों की जांच का ऐसा ही अभियान चलाया जिसमें घर-घर जाकर यह जांच की गई कि कार्ड में दिखाए गए लोग वास्तव में वहां रहते भी हैं या नहीं. खबरों के अनुसार एक डॉक्टर के यहां कार्ड की जांच के दौरान इंस्पेक्टर ने पाया कि उसमें शेरू खां नाम का एक सदस्य भी है. इससे पहले कि डॉक्टर साहब यह बता पाते कि यह उनके नौकर का नाम है जो किसी काम से बाहर गया हुआ है, उनकी नन्ही बेटी ने अपनी मासूमियत भरी उत्सुकता में झट से बता दिया कि यह तो उनके पालतू कुत्ते शेरू का नाम है.

मतवाली चाल

■ पुलिस और अपराधियों के बीच आंखमिचौनी कोई न कोई गुल खिलाती रहती है. कभी इसमें पुलिस जीतती है तो कभी अपराधी. पिछले दिनों मेरठ में भी ऐसा ही एक वाकया हुआ जिसमें एक अभियुक्त ने पुलिसवालों की आंखों में धूल झोंकने का करतब दिखा दिया.

एक निकटवर्ती गांव में हुए अपहरण और हत्या के आरोप में पुलिस उसी गांव के एक व्यक्ति को गिरफ्तार करना चाहती थी. इस सिलसिले में उस व्यक्ति के नाम गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया जा चुका था. लेकिन वह व्यक्ति पुलिस के हाथ में पड़ने के बजाय सीधे अदालत में आत्मसमर्पण करना चाहता था. लिहाजा पुलिस और अभियुक्त के बीच इस बात को लेकर ठन गई कि अभियुक्त पुलिस के हाथ आए बिना अदालत में मजिस्ट्रेट के कमरे तक पहुंच पाता है या नहीं. एक दिन पुलिस को किसी तरह यह खबर मिल गई कि अभियुक्त कचहरी पहुंचकर आत्मसमर्पण करने वाला है. बस फिर क्या था, देखते ही देखते कचहरी पहुंचने के सभी रास्तों पर सिपाही तैनात कर दिए गए ताकि उसे पहले ही पकड़ लिया जाए. लेकिन अभियुक्त भी कम चालाक नहीं था. वह बुर्का पहनकर और पैरों में जनाना चप्पल और पाजेब

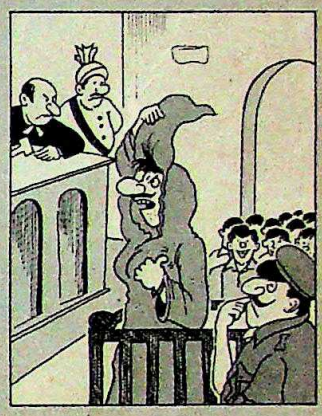

पहनकर पुलिस वालों को छकाता हुआ मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर हो गया. इस हार से खिसियाई पुलिस को बस इसी में संतोष करना पड़ा कि मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

निकला धूम से जनाजा

■ शादी के बारे में अक्सर ऐसा कहा जाता है कि यह ऐसा लड्डू है जिसे खाने वाला भी रोए और न खाने वाला भी. मगर भारत के अधिकांश हिस्सों में जैसी खस्ता हालत टेलीफोन सेवाओं की है उसे

देखकर तो यही लगता है कि यह कहावत शायद मूल रूप से टेलीफोन सेवा के लिए ही बनाई गई थी. देश भर में शायद ही कोई ऐसा स्थान होगा जहां के लोग अपने यहां की टेलीफोन सेवा से संतुष्ट हों. टेलीफोन विभाग की सेवाओं से परेशान उपभोक्ता वैसे तो अपनी नाराजगी अखबारों, पत्रिकाओं और दूसरे समाचार माध्यमों से प्रकट करते रहते हैं पर पिछले पखवाड़े मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के एक कस्बे के व्यापारियों ने जिस अंदाज में अपनी परेशानी का रोना रोया वह बिलकुल अनूठा था.

स्थानीय टेलीफोन अधिकारी एक सुबह यह देखकर दंग रह गए कि एक साथ कई 'अर्थियां' लिये एक विशालकाय जुलूस उनके दफ्तर के सामने आ जमा है. मामला साफ होते बहुत देर नहीं लगी. पता चला कि स्थानीय व्यापार मंडल के लगभग 70 व्यापारी अपने-अपने 'डेड' टेलीफोनों की अर्थियां सजाकर उन्हें ये टेलीफोन वापस लौटाने आए हैं. व्यापारियों की शिकायत थी कि उन्हें या तो ट्रंक काल पर 'नो रिप्लाई' मिलता है या फिर वे बिलकुल ही काम नहीं करते. बेचारे अफसर लोगों की हालत यह थी कि न आश्वासन देते बने और न टेलीफोन की अर्थियां स्वीकार करते.

शिकारी अपने जाल में

■ आतंकवाद से निबटने में लगी पुलिस अपनी ही सतर्कता के कारण अपने लिए कैसे-कैसे सिरदर्द पैदा कर सकती है इसका एक उदाहरण पिछले पखवाड़े कानपुर में देखने को मिला. दिल्ली में वाहन चोरों की गतिविधियों से परेशान पुलिस को खबर मिली कि चोरी में लगे लोगों के कुछ सूत्र कानपुर में पकड़े जा सकते हैं. बस फिर क्या था. दिल्ली पुलिस के अधिकारी हरकत में आए और आधुनिक हथियारों से लैस एक पुलिस दस्ते को कानपुर के लिए रवाना कर दिया गया. यह दस्ता वहां होटल में जा टिका.

लेकिन इससे पहले कि वे चुस्त-दुरुस्त होकर अपना अभियान पूरा करने के लिए बाहर निकलते, स्थानीय पुलिस के हथियारबंद दस्ते ने उनके कमरों को घेर लिया और उन्हें हिरासत में ले लिया. दरअसल दिल्ली से आए मेहमानों का डीलडौल और उनके हथियारों को देखकर होटल मैनेजर को यह शक हो गया कि वे आतंकवादी हैं. उसी के फोन के जवाब में स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई की. हालांकि दिल्ली पुलिस दस्ते ने अपने दस्तावेज दिखाकर उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन कानपुर पुलिस किसी तरह का जोखिम उठाने को तैयार नहीं थी. नतीजा यह हुआ कि दिल्ली पुलिस मुख्यालय से आने वाली पुष्टि में 12 घंटे

लग गए और इसी बीच में मेहमान पुलिस अधिकारियों को लगभग वह सब भुगतना पड़ा जो आम तौर पर उनके हाथों पकड़े गए लोगों को भुगतना पड़ता है.

—संकलन: विजय क्रान्ति

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

देवताओं के स्थल में आपका स्वागत

बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री आकर श्रद्धा-सुमन चढ़ाइये

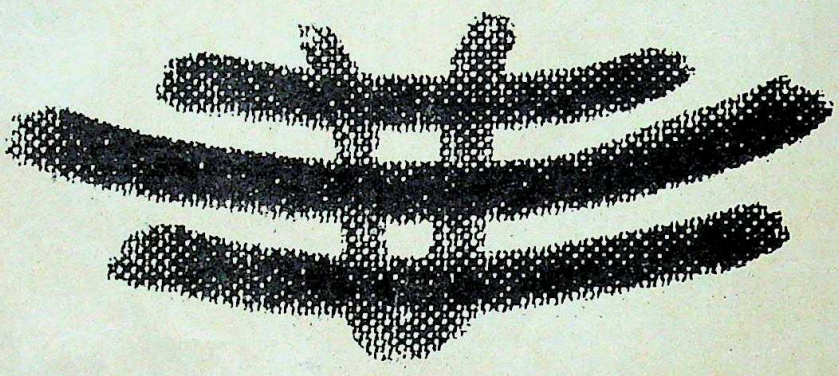

मंदिरों के पट खुलने की तारीख :
बद्रीनाथ– 8 मई केदारनाथ– 6 मई गंगोत्री और यमुनोत्री–19 अप्रैल

निगम मुनि-की-रेती, ऋषिकेश से इन पवित्र मन्दिरों के लिये सम्पूर्ण सुख-सुविधाओं से युक्त यात्राएँ आयोजित करता है। इसमें अत्यंत आरामदायक बसों से यात्रा की व्यवस्था और आवास एवं गाईड़ का उत्तम प्रबंध शामिल है। डीलक्स यात्रा में आरामदायक कोचों में सफ़र का इंतज़ाम, दो व्यक्तियों के लिये सम्मिलित आवास और प्रशिक्षित गाईडों की व्यवस्था भी सुलभ कराई जाएगी।

सम्पूर्ण यात्रा एवं आवास आदि के आरक्षण के लिये बेहतर है कि दो सप्ताह पहले कृप्या निम्नलिखित से सम्पर्क करें :–
सहायक महाप्रबंधक (पर्यटन)
गढ़वाल मंडल विकास निगम लि०
मुनि-की-रेती, ऋषिकेश, फ़ोन : 372/367

गढ़वाल मंडल विकास निगम लि.

74/1 राजपुर मार्ग, देहरादून
टैलेक्स नं. 585-318 द्रोण इन टेलीफ़ोन 26817/26830/26980
निदेशक, उत्तर प्रदेश पर्यटन,
चित्रहार भवन, 3 नवल किशोर मार्ग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

साधारण

1. चारधाम, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ. 11 दिन प्रतिदिन व्यस्क रू 1333/- बच्चा रू. 1100/-
2. ऋषिकेश, केदारनाथ, बद्रीनाथ वाया चीला, पौड़ी. 8 दिन. सोम, मंगल, बुध, बृहस्पत. व्यस्क रू 860/- बच्चा रू. 720/-
3. ऋषिकेश, केदारनाथ, बद्रीनाथ वाया लैंसडाऊन, पौड़ी. 7 दिन, शुक्र, शनि, रविवार. व्यस्क रू 850/- बच्चा रू. 700/-
4. दिल्ली-केदारनाथ, बद्रीनाथ 7 दिन बुध. व्यस्क रू. 1190/- बच्चा रू. 950/-
5. देहरादून, यमुनोत्री, गंगोत्री, गोमुख 7 दिन, मंगल व्यस्क रू 775/- बच्चा रू. 660/-
6. ऋषिकेश, यमुनोत्री, गंगोत्री, गोमुख 7 दिन, सोम. व्यस्क रू. 725/- बच्चा रू. 610/-
7. ऋषिकेश, फूलों की घाटी, हेमकुण्ड 7 दिन, सोम, बृहस्पत. व्यस्क रू. 860 /- बच्चा रू. 715/-
8. ऋषिकेश, बद्रीनाथ (3 x 2बस) 4 दिन मंगल. व्यस्क रू. 430 /- बच्चा रू. 360/-

डीलक्स

1. ऋषिकेश, चारधाम, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ (टूरिस्ट कार द्वारा) 9 दिन मंगल, बुध, रवि. रू. 2450/-
2. ऋषिकेश, केदारनाथ, बद्रीनाथ (टूरिस्ट कार द्वारा) 5 दिन प्रतिदिन रू. 1265 /-
3. ऋषिकेश, केदारनाथ, बद्रीनाथ (मिनी बस द्वारा) 6 दिन. सोम, रवि. व्यस्क रू. 955 /- बच्चा रू. 795/-

गढ़वाल पर निःशुल्क विवरण-पत्रिका प्राप्त करने के लिए हमें अपने पते सहित टिकट लगा लिफ़ाफ़ा भेजें

भक्तों के लिए श्रद्धा-आस्था, तो पर्यटकों के लिए अलौकिक आनन्द ।

आरक्षण के लिए 3 सप्ताह पहले गढ़वाल मंडल विकास निगम लि. के निम्न क्षेत्रीय कार्यालयों से सम्पर्क करें :-
● सहायक प्रबंधक, द्वारा उ.प्र. पर्यटन कार्यालय, 36 जनपथ, नई दिल्ली, फ़ोन : 3326620, 3322251. ● जन सम्पर्क अधिकारी, 2-ए-1, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ.
● सम्पर्क अधिकारी, द्वारा उ.प्र. पर्यटन कार्यालय, 12-A नेताजी सुभाष मार्ग, दूसरी मंज़िल, कलकत्ता, फ़ोन: 220798, 220287 ● जन सम्पर्क अधिकारी (पश्चिमी क्षेत्र) द्वारा आई.टी.डी.सी. निर्मल बिल्डिंग, 11वी मंज़िल, नारीमन पॉइंट, बम्बई. फ़ोन: 2026679, 2023343, 2022575. द्वारा एम.टी.डी.सी. (यात्रा कक्ष), मैडम कामा रोड, बम्बई.
● प्रबंधक (ट्रान्सपोर्ट इकाई) आर.टी.डी.सी., गलोर पर्यटन बंगला, एम.आई. रोड जयपुर, फ़ोन: 60239, टैलेक्स: 365-479.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रहस्य का कोहरा

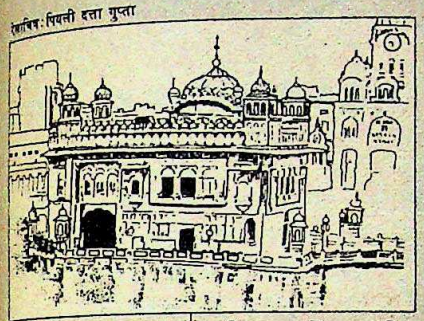
रेखांकन: पियली दत्ता गुप्ता

जोर-आजमाइश और अस्तित्व के संकट ने बीते पखवाड़े पर अपना शिकंजा ऐसा कसा कि सब कुछ रहस्य के कोहरे में ही लिपटता चला गया. आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच चलने वाली लंबी गोलाबारियों ने अमृतसर में सिख पंथ के सबसे पावन केंद्र को एक बार फिर जंग की रणभेरी से गुंजा डाला. हथियारों की चकाचौंध में चौंधियाते स्वर्ण मंदिर में आतंकवादियों की नई मोर्चेबंदी ने ऐसी जोर-आजमाइश की आशंकाओं को रूप देना शुरू कर दिया जो पंजाब समस्या को राजनैतिक असमंजस से भी परे ले जा सकती है.

आतंकवादियों की नई मोर्चेबंदी से ऐसी जोर-आजमाइश की आशंकाएं बलवती हो गईं जो पंजाब को राजनैतिक असमंजस से परे ले जा सकती हैं

हरियाणा में एक विवाह मंडप में हुए हत्याकांड और संसद में विपक्ष के बढ़ते दबाव ने राष्ट्रपति शासन की उपयोगिता पर एक और प्रश्नचिन्ह लगा दिया.

रहस्य के दायरे ने दिल्ली के एक अस्पताल को भी जा घेरा जहां भारतीय सिनेमा की महान हस्ती राजकपूर सांसों के लिए संघर्ष कर रहे थे. बाहर दिन-ब-दिन बढ़ती भीड़ अपने प्रिय अभिनेता का हाल जानने को उत्सुक थी और अंदर लेटा अभिनेता जैसे अपने आखिरी सीन की तैयारी में जुटा हुआ था.

फिल्मी दुनिया का महान शोमैन जैसे अपने आखिरी सीन की तैयारी में जुटा था और लोग बेचैनी से अस्पताल के चक्कर काट रहे थे

भारतीय शांति सेना और तमिल मुक्ति चीतों के बीच चलने वाली रस्साकशी भी अपने अंतिम दौर में पहुंचती दिखाई दे रही थी. श्रीलंका सरकार और प्रतिबंधित सिंहली आतंकवादी संगठन जनता विमुक्ति पेरुमना के बीच होने वाला कोई समझौता भारतीय शांति सेना के लिए एक नई चुनौती पैदा कर सकता है. यानी भारतीय सेना या तो चीतों से हथियार डलवा ले या फिर उन्हें बातचीत की मेज पर ला बिठाए.

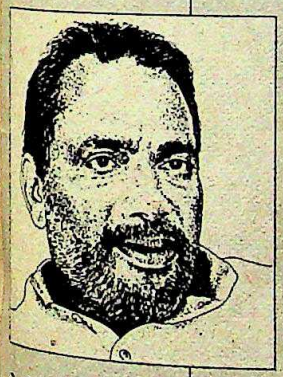

हेगड़े विश्वास मत की अग्नि-परीक्षा में तो खरे उतरे पर बढ़ते भीतरी विरोध के कारण उनके लिए चुनौतियां अभी भी बरकरार हैं

कर्नाटक में सत्ता के रस्से पर दम साधकर चलते रामकृष्ण हेगड़े भी, अस्थायी तौर पर ही सही, अपनी इज्जत बचा पाने में सफल रहे. भले ही विश्वास मत की अग्नि-परीक्षा में वे खरे उतरे पर धड़ाधड़ बरसते इस्तीफों और बढ़ते भीतरी विरोध ने उनके हर बार बच निकलने की योग्यता पर आखिर प्रश्नचिन्ह लगा ही डाला. उनकी समस्याएं फिलहाल खत्म नहीं हुईं. हेगड़े पर पड़ते दबावों और जनता पार्टी को तोड़ने पर आमादा चंद्रशेखर की महत्वाकांक्षा से विपक्ष एक ऐसे मौके पर चक्रव्यूह में घिर गया है जबकि सत्ताधारी दल आक्रामक रुख अपनाने पर उतर आया है. पहले से ही खेमों में बंटे विपक्ष के लिए यह स्थिति निश्चय ही निराशाजनक है. ऐसे में देवीलाल जैसे नेताओं के एक साझी विपक्षी पार्टी बनाने के सपने का क्या होगा और तमिलनाडु अधिवेशन से नया आत्मविश्वास लेकर लौटी कांग्रेस (इ) का मुकाबला वे कैसे कर पाएंगे कहा नहीं जा सकता.

लेकिन देश के राजनैतिक रंगमंच का तख्ता पलट सकने वाली टक्कर होते-होते रह गई. वी.पी. सिंह की चुनौती से मुंह छिपाकर अमिताभ बच्चन ने दिखा दिया कि वह 'शहंशाह' केवल फिल्मी परदे पर ही हैं. इसके साथ यह भी साबित हो गया कि अमिताभ की छवि राजीव के साथ इतनी गहरी जुड़ चुकी है कि चुनाव मैदान में उनके चित होने का मतलब राजीव की ही हार होती.

जनमोर्चा में शामिल होते ही सबसे पहले अशोक सेन ने प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग की

वी.पी. सिंह के जनमोर्चे को भी एक और नया सदस्य मिला— अशोक सेन, जो राजीव के सबसे पहले मंत्रिमंडल में कानूनमंत्री रह चुके हैं. मजेदार बात यह है कि सेन ने ही पूर्व राष्ट्रपति जैल सिंह को 1987 के संकटकाल में राजीव गांधी को बर्खास्त करने के खिलाफ सलाह दी थी. पर मोर्चे में आते ही अपने पहले बयान में उन्होंने राजीव सरकार के इस्तीफे की मांग की.

उधर सत्ताधारी दल के भीतर भी हालत कम हास्यास्पद नहीं थी. उसके ताजातरीन नारे: 'एक व्यक्ति— एक पद' का उद्देश्य तो था कि मंत्रियों की पार्टी पदों पर भी जमे रहने की प्रवृत्ति समाप्त की जाए. लेकिन यह प्रस्ताव इस सचाई से आंखें चुराए रहा कि पार्टी की चोटी पर बैठा व्यक्ति दो-दो गांधी टोपियां पहने हुए है— एक प्रधानमंत्री की और एक पार्टी अध्यक्ष की.

—दिलीप बॉब

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पंजाब

मरने मारने का माहौल

आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के धारावाहिक संघर्ष से 1984 के दुहराने का अंदेशा

अमृतसर में बहुत से लोगों के लिए स्थिति ठीक चार साल पहले जैसे हो गई. स्वर्ण मंदिर के अग्रभाग की छत बालू के बोरों और पक्के मोर्चों के भार से झुक गई थी. 18वीं सदी के दो खस्ताहाल राम-गढ़िया बुर्जों के ऊपर पक्के मोर्चे में नकाबपोश उग्रवादी बंदूकें ताने हुए थे. उधर मंदिर परिसर के इर्दगिर्द की दर्जन भर इमारतों पर सीआरपीएफ (केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल) ने भी मोर्चेबंदी कर रखी थी. स्थिति भयानक हो उठी थी. गोलीबारी लगातार जारी थी. यह कभी-कभार होने वाले उस तरह के धमाके नहीं, जिसके अमृतसर निवासी अब अभ्यस्त हो चुके है बल्कि आगामी लड़ाई के पूर्व संकेत हैं.

यहां से महज 800 गज दूर पुरानी कोतवाली में बड़े-बड़े अफसरों की कतार-सी लग गई थी. उन्हें गंभीर स्थिति से निबटने के लिए चंडीगढ़ से भेजा गया था. पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो वे लोग थे जो नई दिल्ली की उड़ान से पहुंचे थे. अपनी सामान्य काली डांगरियों के बजाय वे सीआरपी की खाकी वर्दी में थे. लेकिन उनके भयानक हथियारों को देखते हुए शक की कोई गुंजाइश न थी कि सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के कमांडो दस्ते को अमृतसर भेजने का फैसला आखिर कर ही लिया है.

कमांडो तत्काल ही उस इलाके में फैल गए. मंदिर के प्रवेशद्वारों के सामने सीआरपी की चौकियों की कमान अब उनके हाथ में थी. पर अमृतसर के उच्चस्तरीय सूत्र कमांडो दस्ते की नई भूमिका के जिक्र को ही गोल कर जाते हैं. एक सूत्र के अनुसार, "चौकी तो कभी भी मोर्चा बन सकती है." लेकिन मूल सवाल यह है कि अगर जरूरत पड़ ही गई तो कमांडो कार्रवाई का आदेश कितनी जल्दी

सभी फोटो: प्रमोद पुष्करणा

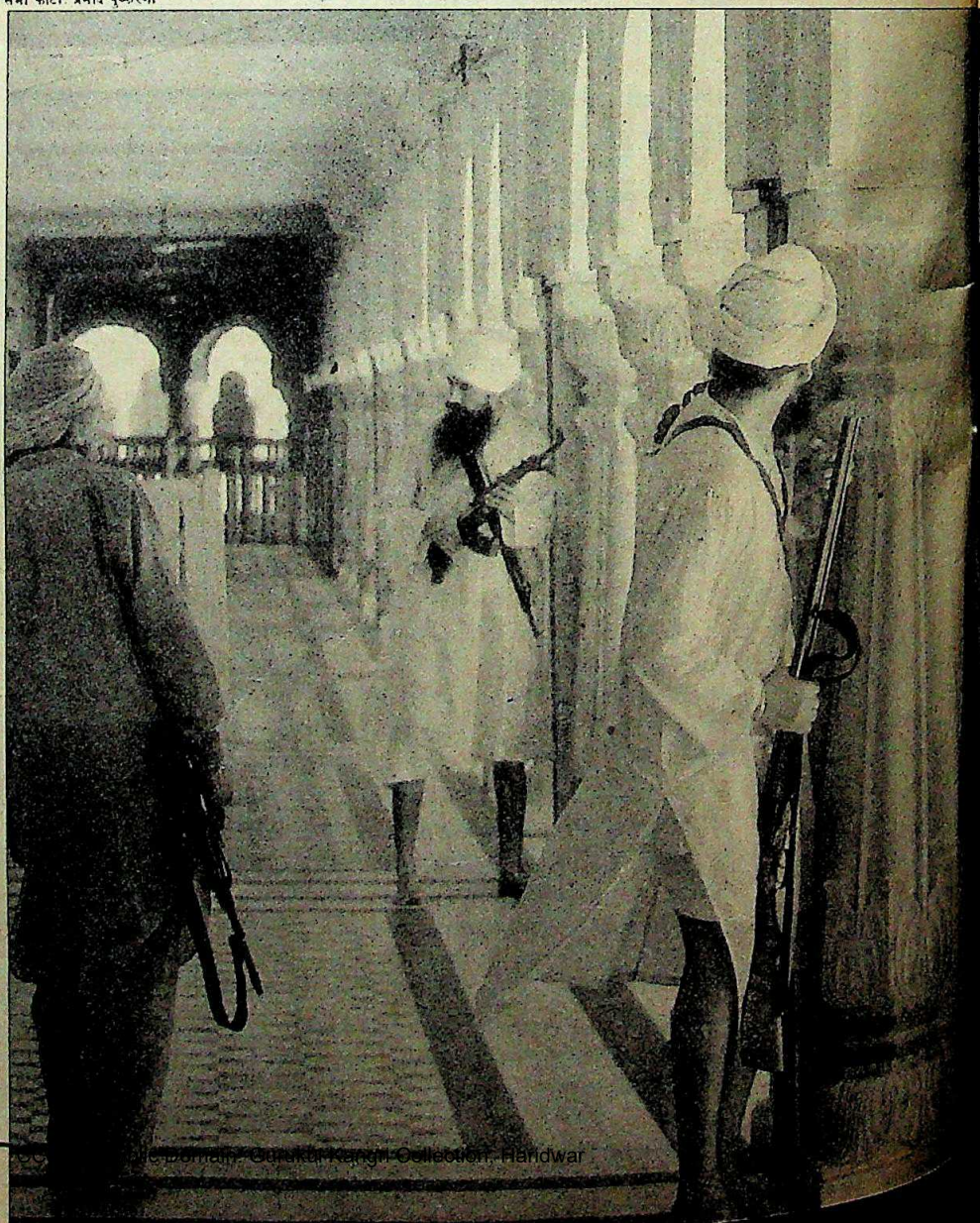

जवानों के चहेते डीआईजी एस.एस. विर्क को आतंकवादियों की गोली लगते ही सीआरपी की त्यौरियां चढ़ गईं और उसने स्वर्ण मंदिर पर अपना शिकंजा कस दिया

CC-0. Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दिया जाएगा. मई 1984 में उग्रवादियों और सीआरपी के बीच ऐसी गोलीबारी होते ही सैनिक कार्रवाई की गई थी. इसके विपरीत इस बार सरकार आतंकवादियों को थकाकर और भूखों मारकर हथियार डालने की ओर ज्यादा प्रवृत दिखी. मंदिर को बिजली और पानी की सप्लाई काट दी गई, बाहर से खाद्यपदार्थों सहित सभी चीजों का भेजना बंद कर दिया गया तथा 800 से अधिक श्रद्धालुओं, महिलाओं और बच्चों को बिना किसी परेशानी के बाहर आने दिया गया.

लेकिन अहम बात यह है कि क्या सरकार अपने पास डटे रहने की हिम्मत है. सात साल पहले पुलिस के एक डीआईजी अवतार सिंह पड़ताल को मंदिर की सीढ़ियों पर ही भून दिया गया था और सरकार देखती रह गई थी लेकिन इस बार वह ज्यादा दृढ़निश्चयी लगी. अंदर फंसे आतंकवादियों द्वारा अपने सहायियों को यह संदेश भेजते ही कि यदि पुलिस ने मंदिर में प्रवेश किया तो वे सारे पंजाब में हत्याओं की लहर शुरू कर दें, जवानों ने मंदिर के इर्दगिर्द घेराबंदी कस दी. उधर पंजाब के तथाकथित नरमपंथी नेता फिर पुरानी चालें चलने लगे. पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की अगुआई में एकीकृत अकाली दल के चार नेताओं ने तो धमकी भी दे डाली कि अगर तत्काल पुलिस नहीं हटाई गई तो वे स्वर्ण मंदिर को मुक्त कराने के लिए सिखों के जुलूस का नेतृत्व करेंगे.

सरकार मुश्किल में पड़ गई. या तो वह कुछ करती या पंजाब में अपनी बची-खुची सत्ता को भी छोड़ देती. संसद में क्रुद्ध सदस्यों ने तत्काल कार्रवाई की मांग की और विपक्ष ने स्थिति को इतना बिगड़ने देने के लिए सरकार को दोषी ठहराया. पिछले तीन हफ्तों से आतंकवादी मंदिर के चारों ओर महत्वपूर्ण स्थानों पर मोर्चाबंदी करते आ रहे थे और सीआरपी के लोग देखते रहे थे. सरकार की दुविधा साफ नजर आती थी. अगर वह मामला बढ़ाए तो इससे उस राजनैतिक पहल का सिलसिला टूट जाने का अंदेशा था जो उसने मार्च में अकाल तखत के मुख्यग्रंथी ज़सवीर सिंह रोडे को रिहा करके शुरू किया

विर्क (ऊपर), बुर्ज पर आतंकवादी (दाएं) और सीआरपी पर गोलीबार

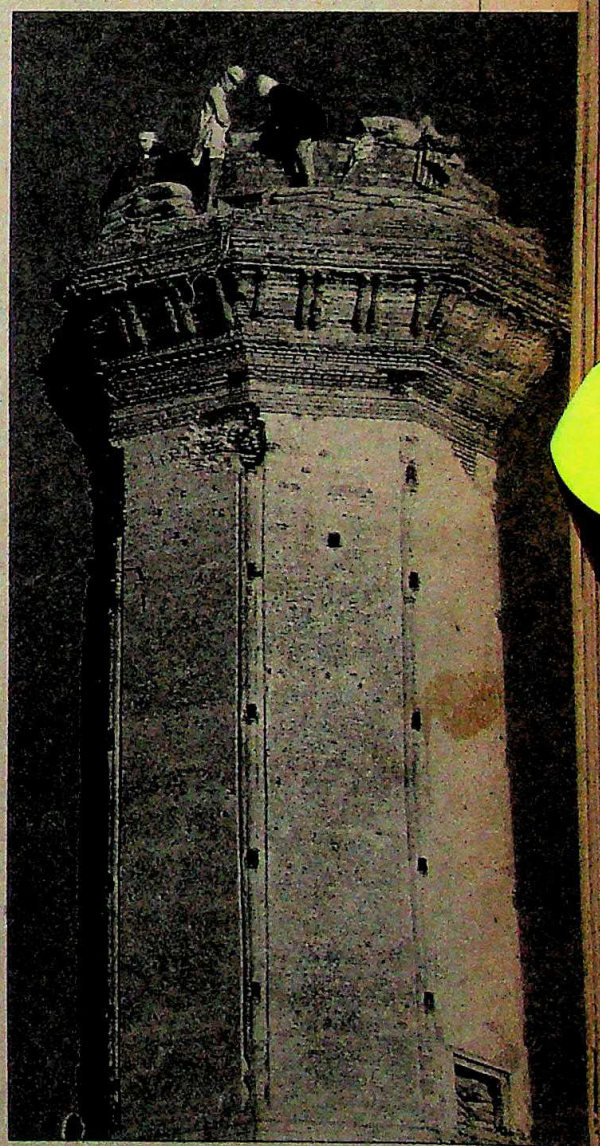

CC-0. Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

था. अगर उसने कुछ नहीं किया तो उग्रवादी इस कदर जड़ें जमा सकते हैं कि उन्हें बाहर निकालना मुश्किल जरूर होगा.

पर सरकार अभी असमंजस में ही थी कि पिछले पखवाड़े तेजी से घूमे घटनाचक्र ने सारा उलझाव मिटा दिया. दो अलग मौकों पर आतंकवादियों ने मंदिर से बाहर आकर पुलिस को खुलेआम लड़ाई के लिए ललकारा. उनकी अगुआई ऐसे जाने-माने हत्यारों के हाथ में थी जिनके नाम पुलिस की हिटलिस्ट में बिलकुल ऊपर हैं. उन लोगों ने एक ऐसे घोषित आतंकवादी को निकल भागने में सहायता के लिए दनादन गोलियां भी चलाईं जिसे पुलिस ने मंदिर की सीढ़ियों पर लगभग पकड़ ही लिया था.

पूरा इलाका बारूद के ढेर पर होने से उसे महज एक चिंगारी की ही जरूरत थी. पर हुआ इससे भी बुरा. 9 अप्रैल की सुबह डीआईजी विर्क ने मंदिर के इर्दगिर्द इमारतों पर अपने जवानों की चौकियों का निरीक्षण करने का फैसला किया. वे देखकर हैरान रह गए कि कुछ उग्रवादी मंदिर परिसर के बाहर की एक ऊंची इमारत पर पक्के मोर्चों का निर्माण कर रहे हैं. ऑपरेशन ब्लूस्टार के बाद तो यह असोमान्य बात थी. विर्क ने उन्हें यह काम बंद करने को कहा. उग्रवादी चुपचाप वहां से हट गए. पर कुछ सेकेंड बाद उनका जवाब भी आ गया. विर्क पर एके-47 गोलियों की बौछार हुई. एक गोली उनके निचले जबड़े को चीरती हुई निकल गई. विर्क के गिरते ही सीआरपी के जवानों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दीं.

विर्क वहां से हटाए गए और सीआरपी की नजदीकी चौकियों तक हमले की खबर पहुंची तो कुछ समय लगा कि मामला हाथ से निकलने ही वाला है. लोकप्रिय अफसर होने के कारण विर्क पर घातक हमले के बारे में सुनते ही जवान आपे से बाहर हो गए. अगर महानिरीक्षक (सीमा) चमनलाल वक्त पर ही बीच में न आते तो उन्होंने मंदिर में नरसंहार कर दिया होता. चमनलाल ने उन्हें ठंडा किया और समझाया कि मंदिर में दाखिल होने का फैसला राजनैतिक स्तर पर नई दिल्ली में ही लिया जा सकता है.

इस बीच विर्क को अमृतसर के श्री गुरु तेगबहादुर अस्पताल पहुंचाया गया. उनका परिवार और सीआरपी के अधिकारी बाहर चिंता में ही थे कि एक जटिल ऑपरेशन के बाद उन्हें खतरे से बाहर घोषित कर दिया गया. होश में आने पर उन्होंने कागज पर जो पहले शब्द लिखे, वे हैं, "मैं ठीक हूं और मेरा हौसला बुलंद है. एक-दो गोलियां मुझे अपने कर्तव्य से विमुख नहीं कर सकतीं." उनके पिता कुलदीप सिंह विर्क कहते हैं, "कई बार मैंने उन्हें अमृतसर से बाहर तबादला करा लेने को

सुरजीत सिंह पेंटा (एकदम बाएं); और (नीचे) जागीर सिंह तथा निरवैर सिंह

पुलिस के मुताबिक मंदिर के भीतर एक लाख रु. इनाम वाले कम-से-कम छह आतंकवादी हैं, इनमें दिल्ली में कई हत्याओं का जिम्मेदार सुरजीत सिंह पेंटा भी है

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

...खबर पहुंची
...ना हाथ से
...अफसर होने
...के बारे में
...र हो गए.
...नलाल वक्त
...ने मंदिर में
...या होता.
...ठंडा किया
...मंदिर में
...सला राज-
...दिल्ली में
...है.
...को अमृतसर
...र अस्पताल
...का परिवार
...अधिकारी
...थे कि एक
...बाद उन्हें
...त कर दिया
...पर उन्होंने
...शब्द लिखे,
...और मेरा
...एक-दो
...कर्तव्य से
...तीं." उनके
...विर्क कहते
...हें अमृतसर
...रा लेने को

...(एकदम
...चे) जागीर
...वैर सिंह

...कहा, पर उनका जवाब हमेशा यही होता है: ...क्या जनरल अपनी जिंदगी को खतरा दिखा-...का तबादला करा सकता है?''

मंदिर के भीतर विभिन्न रैंक के अनेक ...नयोजित 'जनरलों' का अपना ही तर्क था. ...हलों से चल रहे लुका-छिपी के खेल का अब ...त आ रहा था और उन्हें कोई फैसला लेना ...ी था. अगर वे आत्मसमर्पण कर दें तो यह ...वाद के लिए कल्पनातीत पराजय होगी. ...र अगर वे लड़ते रहे तो इससे तबाही के ...वा कुछ हासिल नहीं होगा. गोलीबारी शुरू ...ने के बाद मंदिर में पहले छह घंटों के ...त्यदर्शी रहे पत्रकार कहते हैं कि आतंक-...दियों ने हौसला तो बनाए रखा पर उनके ...चेहरों पर तनाव भी झलकता था.

दरअसल वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कहते ...कि अगर उन्हें काम करने का खुला मौका ...या जाए तो आतंकवादियों को थका देना ...क्य है क्योंकि 1984 की तरह उन्होंने फिर ...दिर के अंदर हथियार जमा करने की गलती ...हाई है. पुलिस के मुताबिक मंदिर के ...तर कम-से-कम छह आतंकवादी ऐसे हैं ...जिनके सिर पर एक-एक लाख रु. का इनाम ...है इनमें सुरजीत सिंह पेंटा भी है जिसकी ...दिल्ली पुलिस को कई मामलों में तलाश है. ...क अफसर कहते हैं, "वहां 50,000 रु. के ...नाम वाले तो बीसियों होंगे."

हालांकि पुलिस को खुली छूट देने के पहले ...रकार को इसके नफा-नुकसान पर बारीकी ...से गौर करना होगा. देर से ही सही पर स्वर्ण ...दिर में पुलिस प्रवेश का पंजाब में बुरा ...असर पड़ेगा. इसके साथ ही आतंकवादियों ...का व्यापक जवाबी हमले को भी नहीं नकारा जा सकता. आतंकवादियों की रण-नीति स्वयंभू लेफ्टिनेंट जनरल मल्कियत सिंह अजनाला ने इस कार्रवाई की पूर्व संध्या पर बनाई. उन्होंने कहा, "1984 में मंदिर में हमारी पूरी फौज मौजूद थी. अब सिर्फ हममें से 10 फीसदी लोग ही यहां हैं. इसलिए हमारा जवाबी हमला पूरे देश में होगा."

जो कुछ चल रहा है उससे नए जत्थेदार रोडे की क्या हैसियत रह जाएगी और उनकी रिहाई से शुरू की गई जोखिम-भरी राजनैतिक पहल का हश्र क्या होगा? पिछले पखवाड़े की घटनाओं के बाद संशयी लोग उनकी भूमिका पर सवाल उठाने लगे हैं. पुलिस के एक वरिष्ठ अफसर ने कहा, "यह पहल अब इतिहास का एक अध्याय भर बनकर रह गई है. और रोडे इस पूरे नाटक में एक मामूली पात्र बनकर रह गए हैं." भाकपा के अमृतसर स्थित बुजुर्ग नेता सत्यपाल डांग ने भी इसी अंदाज में कहा, "उनकी हालत दो नावों में पैर रखने जैसी हो गई. वे तय नहीं कर पाए कि भिंडरांवाले का अनुसरण करें या दर्शन सिंह रागी का."

ऐसी दलीलें हालांकि रोडे के समर्थकों के गले के नीचे नहीं उतरतीं पर ताजा घटनाक्रम के चलते वे बचाव का रुख अपनाने को मजबूर हो गए हैं. रोडे ने राजनैतिक रूप से बेवक्त पर जो कदम उठाए उससे भी उनके समर्थकों की स्थिति कमजोर हुई. जब स्वर्ण मंदिर में पहली दफा गोली चलनी शुरू हुई तब वे पटियाला में पंजाबी विश्वविद्यालय के परिसर में आयोजित सभा में बोल रहे थे. और जब दूसरे दिन वे बाकी मुख्यग्रंथियों के साथ स्वर्ण मंदिर जाने के लिए पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया. उन्हें रोकने की पुलिस के पास जायज वजहें भी थीं. इस तरह रोडे को यह प्रमुख कार्रवाई किनारे रहकर ही देखनी पड़ी.

यही नहीं गोलीबारी से ठीक पहले रोडे परिक्रमा से अपना निवास बदलकर गुरु नानक निवास की ऊपरी मंजिल पर ले गए. इससे भी उनकी स्थिति कमजोर हुई. उनका यह कदम 1984 में उनके चाचा भिंडरांवाले के उठाए कदम से ठीक उलटा था. भिंडरांवाले आखिरी मौका करीब आने पर सराय से निकलकर मंदिर परिसर में आ गए थे. हालांकि रोडे के प्रेस सचिव सुखजिंदर सिंह ने सफाई दी थी कि उनका निवास उनसे मिलने वालों की भारी संख्या के लिहाज से काफी छोटा और असुविधाजनक था. लेकिन यह बात नहीं भुलाई जा सकती कि उनका निवास सीआरपी के बालू के बोरों से घिरे मोर्चे और आतंकवादियों के मोर्चों के ठीक बीच में पड़ता था. और रोडे की निश्चित ही दुतरफा गोलीबारी के बीच फंसने की कोई तमन्ना नहीं थी. लेकिन जहां तक सिख आतंकवादियों के बीच उनकी राजनैतिक भूमिका का सवाल है उनका यह कदम नुकसानदेह साबित हुआ. खालिस्तान समर्थक पंथक कमेटी के प्रवक्ता निरवैर सिंह ने विद्रोह के मूड में कहा, "उनसे पूछिए कि यदि हालात और बदतर होते हैं तो क्या वे अपना निवास फिर बदल लेंगे. हो सकता है कि वे सीआरपी की चौकी की ओर ही चल दें?"

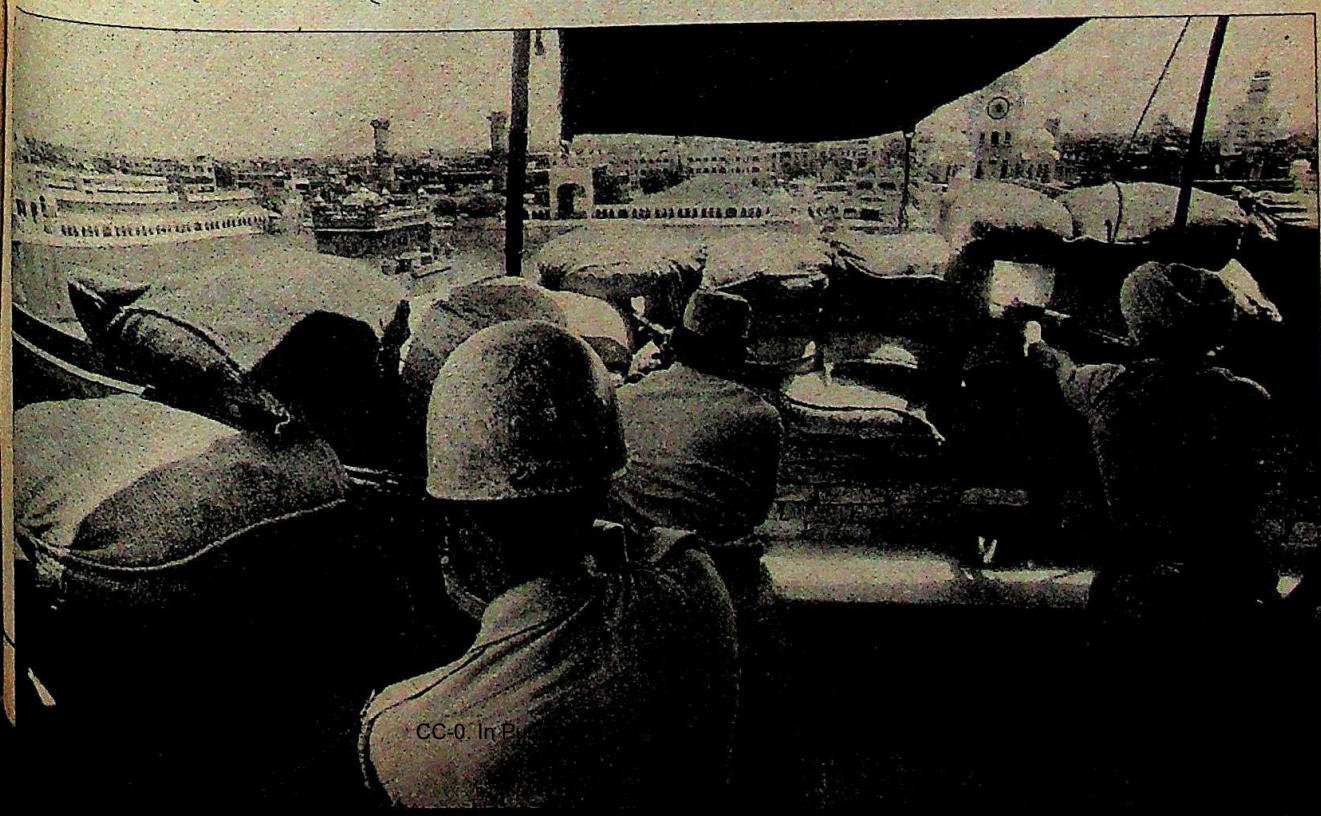

मंदिर पर निगाह रखे हुए सीआरपी के जवान

CC-0. In P...

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

निरवैर सिंह की ही तरह सुपरिचित जागीर सिंह भी सिख उग्रवाद की सबसे अतिवादी धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं और वे खालिस्तान का न समर्थन करने वाले किसी भी व्यक्ति का साथ स्वीकार करने से इनकार करते हैं. जागीर सिंह का कहना है, "इन सभी लोगों को एक बात ठीक से समझ लेनी चाहिए कि खालिस्तान बन गया है. हमें तो अब सिर्फ कब्जा भर लेने की ही जरूरत है." तथाकथित खालिस्तान कमांडो फोर्स के एक धड़े का नेतृत्व करने वाले मल्कियत सिंह अजनाला जैसे मंदिर के अंदर काबिज रोडे के समर्थक भी लगभग यही बात कहते हैं. पर उनका दावा है कि मुख्यग्रंथी उनके साथ हैं. मल्कियत सिंह का कहना है, "वे सिख हितों के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेंगे." मल्कियत सिंह इस दलील को नहीं मानते कि रोडे अब तक खालिस्तान शब्द से बचते रहे हैं.

पर रोडे को ऐसे समर्थनों से मामूली संतोष ही हो सकता है क्योंकि सभी आतंकवादी संगठनों को 'एक केसरिया झंडे के नीचे' लाने की उनकी कोशिशें कई कारणों से लड़खड़ा रही हैं. इसकी एक वजह तो यह है कि आतंकवादी कई गुटों में बंटे हुए हैं और दूसरे, वर्तमान राजनैतिक हालत और उसमें उनकी भूमिका के बीच जबरदस्त विरोधाभास है. मसलन पिछले पखवाड़े रोडे ने दुनिया भर में दिखाए जाने वाले बीबीसी के टेलीविजन इंटरव्यू में साफ-साफ कहा था कि संविधान के ढांचे में यदि 'सिखों के सभी अधिकार' मान लिए जाएं तो समझौता होने की संभावना है. लेकिन दूसरे ही दिन उग्रवादी हलके की आलोचना के बाद उन्होंने उसका खंडन कर दिया. हालांकि बीबीसी के नई दिल्ली ब्यूरो प्रमुख मार्क टुली का दावा है कि उनका यह बयान टेप किया हुआ है.

मौजूदा हालात में यदि सरकार मंदिर पर दबाव कम करने का फैसला करे और युद्धविराम की बातचीत में उन्हें प्रमुख भूमिका निभाने की मंजूरी दे, तभी रोडे की पहल फिर से आगे बढ़ सकती है. गोलीबारी शुरू होने के दो दिन बाद दो घंटे के अघोषित युद्ध विराम के दौरान उनके दूतों को उग्रवादियों के लिए फल और खाद्य-पदार्थों के साथ मंदिर के भीतर जाने की अनुमति दी गई. अमृतसर में सूत्रों ने बताया कि यह और कुछ नहीं बल्कि उनकी विश्वसनीयता घटने की रफ्तार कम करने का ही एक प्रयास है. इस पहल का एक और मकसद यह भी है कि सरकार बाद में होने वाली इस आलोचना से बचना चाहती है कि कड़ा कदम उठाने से पहले उसने हालात संभालने की कोई चेष्टा नहीं की.

लेकिन मंदिर के भीतर के आतंकवादियों पर सरकार दबाव बरकरार रखे या नहीं, इसका फैसला करते समय सरकार को हमेशा रोडे के भविष्य को ध्यान में रखना होगा. वैसे भी यह फैसला काफी असुविधाजनक है. यदि सरकार रोडे के नुकसान की परवाह किए बगैर दबाव बढ़ाने का फैसला लेती है तो इससे वह उदार सिखों का भी समर्थन खो बैठेगी क्योंकि चाहे जिस किसी वजह से स्वर्ण मंदिर में पुलिस प्रवेश करे थोड़े से सिख ही यह कार्रवाई स्वीकार करेंगे. इससे उसकी अब तक की उदार नीति भी बदलेगी और इससे मिली थोड़ी बहुत सफलताओं पर एक बार और पानी फिर जाएगा. और यदि सरकार अपना रुख नरम करती है तो इससे उसकी छवि पर भारी प्रभाव पड़ेगा. खासकर ऐसी हालत में जब पिछले पखवाड़े हरियाणा के पानीपत में एक खानाबदोश जाति की लड़कियों की शादी के अवसर पर आतंकवादियों द्वारा किए गए नरसंहार से पंजाब की मौतों से कुछ हद तक असंवेदनशील हो चुका राष्ट्र फिर दहल उठा हो.

—शेखर गुप्ता, अमृतसर में

अकाल तखत के नमूने के नीचे पड़ा शव (ऊपर) और मंदिर से बाहर आते श्रद्धालु

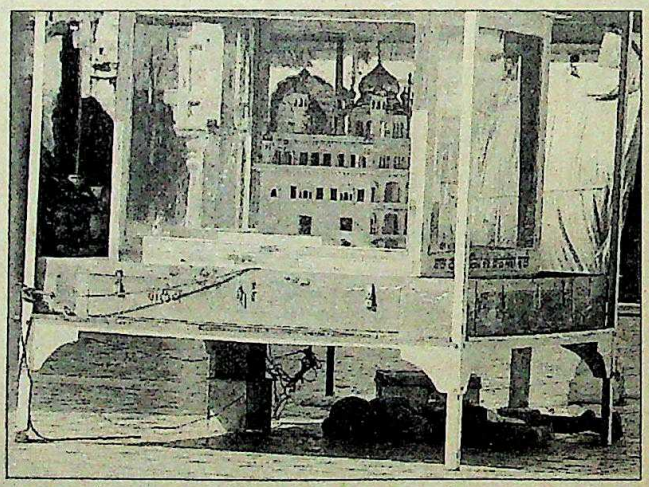

रोडे की साख तभी लौट सकती है जब सरकार मंदिर में बैठे आतंकवादियों पर दबाव कम करके जत्थेदार को सुलह-सफाई की बातचीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का मौका दे

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

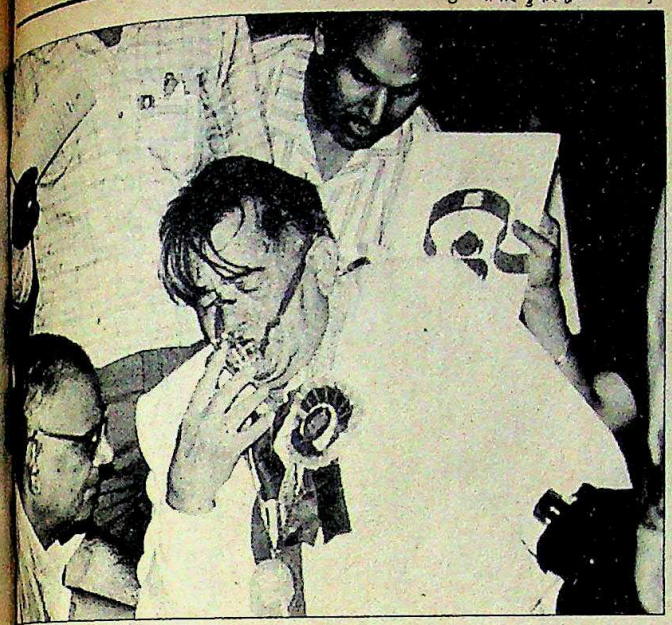

एस.के. चड्ढा, टाइम्स ऑफ इंडिया

समारोह के दौरान दमे का दौरा (बाएं) राजीव के साथ कृष्णा कपूर

राजकपूर

दवा और दुआ के सहारे

हिंदी फिल्मों के बुजुर्ग शोमैन का भावुकतापूर्ण सीन

"हे भगवान! अभी तो मेरा खेल शुरू ही हुआ है. मुझे अभी मत उठाओ. मैं नहीं समझता कि मैं जिस ऊंचाई पर पहुंचना चाहता था, उसके आसपास भी पहुंच पाया हूं." साल भर पहले सिमी ग्रेवाल ने राजकपूर पर एक वृत्तचित्र बनाया, उस दौरान उन्होंने ये शब्द कहे थे.

यह एक विचित्र पूर्वाभास था क्योंकि पिछले पखवाड़े 64 वर्षीय राजकपूर लगभग मौत के जबड़ों में ही जा पहुंचे थे. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एआईआई-एमएस) के एक ठंडे सफेदी पुते कमरे में आज भी जिंदगी के लिए उनकी जद्दोजहद जारी है.

दो मई को हिंदी फिल्म जगत का सर्वाधिक प्रतिष्ठापूर्ण दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने के तुरंत बाद ही रात आठ बजे उन्हें अस्पताल के गहन चिकित्सा कक्ष में लाया गया था. तब से राजकपूर के मुंह से एक भी लफ्ज नहीं निकला है.

दर्जन भर नर्सें खामोशी से उनके बिस्तर के आसपास मंडराती रहती हैं. राजकपूर की नीली सपनीली आंखें बंद हैं और नाक में एक नली लगी हुई है. उधार की सांसों से उनके फेफड़े हरकत में हैं. डॉक्टर उन्हें बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन दे रहे हैं. उनका इलाज कर रहे हृदयरोग विशेषज्ञ और उनके मित्र डॉ. त्रेहन बताते हैं, "ज्यों ही वे आंखें खोलते हैं, हम उन्हें बेहोश कर देते हैं. हम नहीं चाहते कि उनके श्वसन-तंत्र पर अधिक दबाव पड़े."

अस्पताल के बाहर भीड़ बढ़ती जा रही है. लोग चिलचिलाती धूप में खामोशी से इंतजार करते रहते हैं कि कोई बाहर आए और उन्हें अंदर का हाल बताए.

दादा साहब फाल्के पुरस्कार राजकपूर की सफलता और उपलब्धियों का अंतिम पड़ाव था. भारत के सिने संसार में इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं. उनकी बेटी रीमा कहती हैं, "यह उन्हें मिल सकने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सम्मान है. वे पहले भी अपने पिता के लिए यह पुरस्कार ग्रहण कर चुके हैं."

उस दिन समारोह के दौरान राजकपूर एक बार सभागार से उठकर बाहर गए और फिर किसी तरह लौटकर आए. वहां मौजूद दूरदर्शन टीम के एक सदस्य बताते हैं कि जब राजकपूर का नाम पुकारा गया तो उन्हें दमे का दौरा पड़ा हुआ था. वे विचलित से लग रहे थे. "उनकी पत्नी ने जब मंच की ओर इशारा किया तो वे कुछ समझे नहीं." जब राष्ट्रपति खुद पुरस्कार देने उनकी सीट तक पहुंचे तब तक हिंदी फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े शो मैन के नाखून नीले पड़ने लगे थे.

फिर भी राजकपूर भाग्यशाली रहे. राष्ट्रपति के निजी चिकित्सक उनके पास ही बैठे थे और एंबुलेंस बाहर खड़ी थी. उन्हें ठीक समय पर एआईआईएमएस पहुंचा दिया गया.

अस्पताल में डॉक्टरों ने पाया कि उन्हें महज दमे का ही दौरा नहीं पड़ा था. प्रति मिनट 10 से 15 लिटर ऑक्सीजन दिए जाने के बावजूद उनके खून में ऑक्सीजन की बेहद कमी हो गई थी. डॉक्टरों ने उनकी छाती को सुन्न कर दिया और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाकर शत-प्रतिशत कर दी. इससे भी गंभीर बात थी कि राजकपूर के फेफड़े निमोनिया से प्रभावित हो चुके थे. एआईआईएमएस के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. ए.एन. सफाया बताते हैं, "वे अभी इतने बूढ़े नहीं हुए लेकिन वे जवान भी नहीं हैं. हम जानते थे कि उन्हें बचाने के लिए हमें लंबे समय तक जूझना पड़ेगा."

16 साल में पहली बार इकट्ठा हुए कपूर खानदान के सभी सदस्यों की नजरें अपने मुखिया पर ही टिकी हुई हैं. मंदिरों और गुरुद्वारों में उनके लिए प्रार्थना करते, सुबह से रात तक वे वहीं जमे रहते हैं. राजकपूर की पत्नी और उनके जीवन का संबल कृष्णा दिन रात अस्पताल में ही रहती हैं. उन्हें और दिलीप कुमार को ही राजकपूर को देखने की इजाजत डॉक्टरों ने दी थी.

पिछले पांच वर्षों से राजकपूर का स्वास्थ्य बिगड़ता ही जा रहा था. वे दमे के पुराने मरीज हैं. दमे के कारण फेफड़े खराब हो गए थे. सांस लेने में उन्हें तकलीफ होती थी.

राजकपूर के प्रशंसकों और हिंदी फिल्म दर्शकों की चिंता स्वाभाविक है. कपूर खानदान फिल्मों के जरिये सार्वजनीन हो गया है. उनके जीवन और प्रेमगाथाओं से दर्शकों

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

की चार-चार पीढ़ियां प्रभावित हुई हैं. ऐसा कौन सा दर्शक है, जिसने 'बरसात' फिल्म देख कर नर्गिस के लिए राजकपूर के प्रेम से ईर्ष्या न की हो या 'बॉबी' देखकर प्रेम में डूबे किशोर की विह्वलता का अनुभव न किया हो. टखनों तक पैंट मोड़े राजकपूर भारतीय सिनेमा के जैसे चार्ली चैप्लिन थे. वे उस दुनिया के प्रतीक थे, जहां जीवन में मासूमियत थी, प्यार था, ऐसा प्यार जो आज शायद संभव नहीं. नर्गिस की आंखों में झांकने के अंदाज से ही उन्होंने चाह के लिए चाह और प्रेम के लिए प्रेम पैदा किया. उनकी पुरानी फिल्में कई बार देखने वाली 54 वर्षीय गृहिणी चंदन अरोड़ा कहती हैं, "यह जोड़ा वाकई रोमांचित कर देता था."

राजकपूर एक पीढ़ी विशेष के फिल्मकार नहीं हैं. अपने युग की हर पीढ़ी की नब्ज पहचानने की दक्षता उनमें गजब की है. चाहे 'बॉबी' हो या आखिरी फिल्म 'राम तेरी गंगा मैली'. वे ऐसे निर्देशक हैं जो अपनी फिल्मों में पवित्रता के आवरण में नग्नता के दृश्य बखूबी दिखा सकते हैं और भौंडेपन से बचते हुए कामोत्तेजक दृश्यों की रचना कर सकते हैं. उन्हें एक बुद्धिजीवी निर्माता तो नहीं कहा जा सकता लेकिन दर्शकों के मर्म छूने की कला उन्हें आती है. फिल्म स्तंभ लेखिका देवयानी चौबल ने कहा, "राज कपूर के अभाव में फिल्मी दुनिया अपना सबसे बड़ा प्रेमी गंवा बैठेगा."

तीन मई से ही उनके स्वास्थ्य की खबरें राष्ट्रीय अखबारों के पहले पन्ने पर जगह पाती रही हैं. इतवार को दूरदर्शन ने उन पर तैयार किया गया सिमी ग्रेवाल का वृत्तचित्र 'द लिविंग लीजेंड' दिखाया. जिसने इसे देखा, अवाक होकर देखता रहा. वीडियो पार्लर के मालिक भी मानते है कि आजकल आर.के. फिल्म्स की फिल्मों की मांग जोरों पर है—खासकर पुरानी फिल्मों की जिनमें राज कपूर ने एकाकी, आवारा लेकिन प्यार के भूखे युवक का रोल किया है.

एआईआईएमएस में आने वालों का सैलाब थमा नहीं है. उन्हें देखने आने वालों में प्रधानमंत्री राजीव गांधी और बलराम जाखड़ भी शामिल हैं. बंबई से तो तकरीबन सभी फिल्मी सितारे आए. अस्पताल के बाहर थोड़ी-थोड़ी देर बाद उनके स्वास्थ्य से संबंधित सूचनाएं जारी की जातीं हैं.

आने वालों में साधारण, छोटे तबके के लोग भी हैं, जो अपने ढंग से राजकपूर को चाहते आए हैं. अहमदाबाद का एक बूटपालिश करने वाला अपनी जिंदगी भर की बचत खर्च करके यहां तक चला आया.

अब से पहले एआईआईएमएस के सामने इतनी भीड़ नहीं रहती थी. इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अस्पताल वालों को दिल्ली पुलिस की सहायता लेनी पड़ी. कुछ लोग तो आने वाले फिल्मी सितारों को देखने के लिए आते हैं. लेकिन ज्यादातर हर पल राजकपूर के साथ ही जी रहे हैं—उनकी दीर्घायु की प्रार्थना करते, अगले समाचार बुलेटिन की प्रतीक्षा करते. राजकपूर की जिंदा रहने की ख्वाहिश शायद पूरी हो जाए.

—सिमरन भारद्वाज

प्रशांत पंजियार

पाना इंडिया

पाना इंडिया

स्वास्थ्य बुलेटिन (ऊपर); कपूर खानदान (बीच में); और (नीचे) डिंपल के साथ राज की बेटी रीतू

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जनता पार्टी

यादवी संघर्ष

इंका को खुशी ही होगी

अगर इंका अध्यक्ष राजीव गांधी किसी ऐसे शख्स को पुरस्कृत करने की तलाश में हैं जिसने पिछले कुछ महीनों में उनकी पार्टी की स्थिति मजबूत की हो तो उन्हें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं. इस दिशा में लगातार काम कर रहा शख्स प्रधानमंत्री निवास 7, रेसकोर्स रोड से थोड़ी ही दूर 3, साउथ एवेन्यू लेन में रहता है.

लेकिन दिक्कत यही है कि यह आदमी इंका में नहीं है. चर्चित व्यक्ति हैं जनता पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर, जिन्होंने पार्टी पर अपना पूरा नियंत्रण बनाए रखने के चक्कर में सारे संगठन को अस्त-व्यस्त कर रखा है और उसे टूटने के कगार पर पहुंचा दिया है.

चंद्रशेखर की वजह से ही मजबूत विपक्षी मोर्चा बनाने की सारी कोशिशें बेकार रही हैं. साजिशों के जरिये उन्होंने रामकृष्ण हेगड़े की कर्नाटक सरकार को करीब-करीब गिरा ही दिया था. उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि विधान परिषद चुनाव में पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार हार गया और दो विधायकों को पार्टी से निलंबित कर देना पड़ा.

पिछले पखवाड़े पार्टी टूटने के आसार दिखने भी लगे जब पार्टी के अंदर संघर्षरत गुटों ने एक-दूसरे के खिलाफ मुहिम तेज कर दी. इस मुहिम में एक ओर चंद्रशेखर-अजीत सिंह-सुब्रमण्यम स्वामी का त्रिगुट था तो दूसरी ओर हेगड़े-दंडवते-मेनका का त्रिगुट.

पार्टी में कुछ दिन पहले शामिल हुए कार्यकारी अध्यक्ष अजीत सिंह बिना किसी लाग-लपेट के बात करते हैं. क्या हेगड़े और दंडवते के पार्टी छोड़ने की सूरत में भी आप अध्यक्ष बनने पर जोर देंगे, यह पूछे जाने पर उनका जवाब था, "वे कहां जा सकते हैं? असली लड़ाई तो उत्तर भारत में होगी जहां न उनकी कोई पूछ है, न आधार."

दूसरा गुट भी उतना ही भिड़ने के मूड में था. एक चिट्ठी में मेनका ने चंद्रशेखर को उत्तर प्रदेश के संकट का जिम्मेदार ठहराते हुए उन पर पार्टी मामलों में 'बनिया मानसिकता' बरतने का आरोप लगाया. 'कांग्रेस से जुड़े गोरखपुर के एक माफिया सरदार' से उनके रिश्तों का जिक्र करते हुए मेनका ने अपनी चिट्ठी में गाली-गलौज से थोड़ी कम तीखी भाषा का प्रयोग किया है.

यह गुस्सा पार्टी से मेनका समर्थक दो विधायकों अकबर अहमद 'डंपी' और वीरेंद्र प्रताप शाही के निकाले जाने पर फूटा था. चंद्रशेखर ने इन दोनों पर बागी उम्मीदवार रामकरण सिंह को वोट देने का आरोप लगाया जिसके परिणामस्वरूप पार्टी उम्मीदवार अब्दुल रऊफ लारी हार गए थे.

दरअसल उत्तर प्रदेश में उठी समस्या की जड़ें कर्नाटक में हैं, जहां चंद्रशेखर ने हेगड़े का 'जीना' दुश्वार कर रखा है. हेगड़े ने बदले में पार्टी अध्यक्ष को तंग करने के लिए उत्तर प्रदेश में मेनका गांधी की मदद ली. बताया जाता है कि कम-से-कम 12 विधायकों ने पार्टी उम्मीदवार को वोट न देकर रामकरण को जिताया.

यह हार महत्वपूर्ण थी क्योंकि चंद्रशेखर गुट राज्य के 80 विधायकों का समर्थन पाने का दावा कर रहा था. अजीत सिंह के लिए भी यह एक करारा झटका था क्योंकि विलय से पहले लारी लोकदल (अ) में थे.

घरेलू अखाड़े में पटखनी खाने के बाद अजीत सिंह को भी ताव आ गया, "हम पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेंगे. यह तो मेनका गांधी को देखना चाहिए था कि उनके समर्थक पार्टी के विरुद्ध मतदान की खुलेआम घोषणा नहीं करते. ऐसे निष्कासन वापस नहीं लिया जा सकता." जनता पार्टी में उनकी स्थिति मोरारजी देसाई की चिट्ठी से भी मजबूत हुई जिसे सुब्रमण्यम स्वामी उनके पक्ष में लिखवा लाए थे. चंद्रशेखर को लिखी इस चिट्ठी में देसाई ने उन्हें पदमुक्त होने के बाद अजीत सिंह को अध्यक्ष की कुरसी सौंपने की सलाह दी. यह बात चंद्रशेखर को भी रास आई.

लेकिन यह कहना आसान है, करना मुश्किल. चंद्रशेखर के उत्तराधिकारी की पुष्टि विलीन हुई तीनों पार्टियों के लोगों को लेकर बनी तदर्थ राष्ट्रीय कार्यकारिणी से होनी जरूरी है. इस सिलसिले में दो महत्वपूर्ण बैठकें पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जा चुकी हैं. अजीत सिंह, चंद्रशेखर, हेगड़े, दंडवते और रामनरेश यादव की पांच सदस्यीय चयन समिति की पहली बैठक ही 5 मई को अजीत सिंह के अनुपलब्ध रहने से संभव नहीं हो पाई.

फिलहाल तीनों पार्टियां राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अपने-अपने प्रतिनिधित्व के सवाल पर उलझी हुई हैं. अभी जनता पार्टी के 40, लोकदल (अ) के 30 और संजय विचार मंच के पांच सदस्य हैं. ऐसी स्थिति में जनता पार्टी के 20 और लोकदल (अ) के सभी लोगों का समर्थन पाकर चंद्रशेखर का खेमा मजबूत है. लेकिन मेनका ने अपनी कार्यकारिणी के 32 नामों की नई सूची भेजकर एक और हंगामा खड़ा कर दिया है. हालांकि जनता पार्टी के नेता दिखावा कर रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होगा पर इतना साफ है कि अजीत के लिए अध्यक्ष बन पाना आसान नहीं होगा.

इंतजार की इन घड़ियों में अजीत सिंह की बैचेनी बढ़ती जा रही है. पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के अधिकार जताने के अंदाज में वे कहते हैं, "हम पार्टी को लंबे समय तक सोते नहीं रहने दे सकते. मुझे कुछ करना ही होगा." वे क्या करेंगे, यह उन्होंने नहीं बताया. पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगता है कि वे पार्टी की प्रदेश इकाइयों के अध्यक्षों और आगामी उपचुनावों के लिए उम्मीदवारों के चयन पर कोई कार्रवाई कर सकते हैं.

पार्टी के महासचिव यशवंत सिन्हा समस्याओं की अनदेखी करके कहते हैं, "संकट, विवाद और सर्वसम्मति जनता पार्टी के स्वभाव के अनुरूप ही है." लेकिन इससे पार्टी कार्यकर्ताओं को कोई ढाढ़स नहीं मिलने वाला. किस नेता का साथ दें, फिलहाल वे इसी दुविधा में पड़े हैं.

—पंकज पचौरी

चंद्रशेखर: इस्तीफे की दुविधा

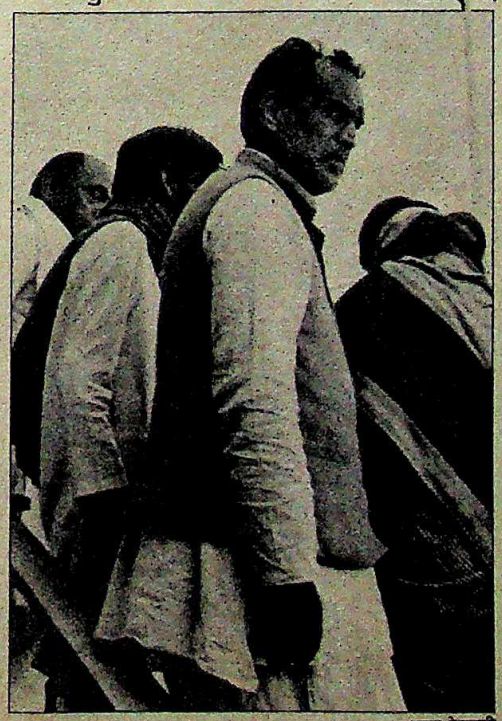

श्याम टेकवानी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

श्रीनिवास कुमार

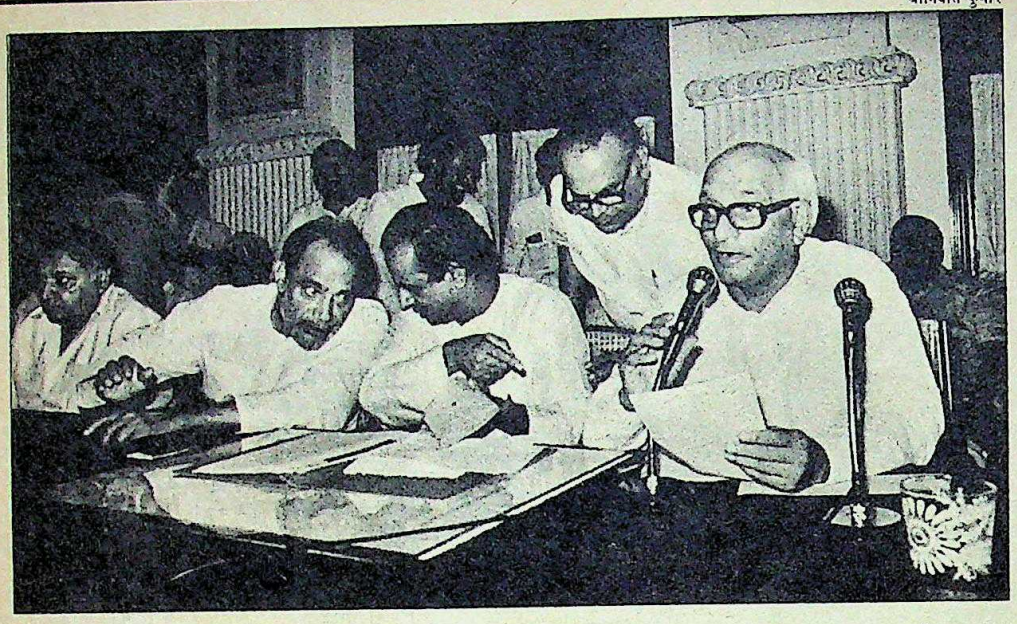

हेगड़े (बाएं), दंडवते (माइक पर); पक्षपात का आरोप

कर्नाटक

जीते मगर आन न रही

हेगड़े के मुकाबले असंतुष्ट हार कर भी पीछे हटने तैयार नहीं

और अंततः मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े पिछले पखवाड़े कर्नाटक में जनता विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक से विजयी होकर निकले. लेकिन उस लड़ाई में उन्हें फतह हासिल नहीं हुई है जो उनके नेतृत्व के लिए खतरनाक बनती जा रही है. नौ घंटे की बैठक के बाद हेगड़े ने कहा, "मैं चुक गया हूं. मैं जरा भी खुश नहीं हूं."

उनकी निराशा अकारण नहीं है. जनता विधायक दल के 157 में से 42 सदस्यों ने जता दिया कि उनका हेगड़े में भरोसा नहीं है. अब हेगड़े यह दावा नहीं कर सकते कि वे राज्य में अपनी पार्टी के एकछत्र नेता हैं.

विधायकों की बैठक बुलाए जाने तक मतभेद दूर करने की पुरजोर कोशिश की गई. पार्टी आलाकमान के दूत पी.के. अण्णा पाटील असंतुष्ट नेता एच.डी. देवगौडा और हेगड़े के बीच समझौता कराने में सफल हो गए थे. इस समझौते के मुताबिक पूर्व सिंचाई-मंत्री गौडा और उनके समर्थकों को हेगड़े के पक्ष में वोट डालने थे. इसके बदले में मुख्यमंत्री को छह महीने के भीतर अपना पद छोड़ देना था. समझौते को अंतिम रूप देने के लिए दोनों को 30 अप्रैल को नई दिल्ली बुलाया गया. लेकिन गौडा मुकर गए. उनका कहना था कि उनके समर्थक इस समझौते को किसी भी सूरत में नहीं मानेंगे.

इसके बाद हेगड़े के वफादार विधायकों और असंतुष्टों के बीच 3 मई को शक्ति परीक्षण अवश्यंभावी हो गया. जपा विधायक दल की बैठक में असंतुष्टों ने केंद्रीय पर्यवेक्षक मधु दंडवते को पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर की वह चिट्ठी पढ़ने के लिए कहा जिसमें और कोई रास्ता न रहने पर गुप्त मतदान करने का निर्देश दिया गया था. दंडवते गुप्त मतदान के खिलाफ थे और उन्होंने चिट्ठी पढ़ने से इनकार कर दिया. इसके बाद हंगामा शुरू हो गया. गौडा मेज थपथापते हुए दंडवते पर पक्षपात का आरोप लगाने लगे.

इसी समय कृषिमंत्री और हेगड़े के वफादार आर.वी. देशपांडे ने एक सुझाव देकर हेगड़े को संकट से उबार लिया. उन्होंने प्रस्ताव किया कि जो लोग खुला मतदान चाहते हैं वे हॉल में सबसे पीछे चले जाएं. जवाब में सिर्फ 41 लोग पीछे गए. इस पर हेगड़े की हिम्मत बढ़ी और उन्होंने गुप्त मतदान की मांग मान ली. बाजी हाथ से निकलती देख गौडा गुट हेगड़े का समर्थन करने के लिए राजी हो गया. शिक्षामंत्री और हेगड़े के वफादार जीवराज अल्वा बताते हैं, "थोड़े समय के लिए सचमुच सब कुछ ठीक हो गया था."

लेकिन खुशी ज्यादा समय तक नहीं रही. जनता सांसद एम.एस. गुरुपदस्वामी और सरोजिनी महिषी ने गौडा को समझाया कि जपा विधायक दल द्वारा "हेगड़े की सरकार में सर्वसम्मति से आस्था जताने" का प्रस्ताव आपत्तिजनक है क्योंकि इसमें गौडा के दृष्टिकोण का जिक्र नहीं है. चंद्रशेखर के मार्गनिर्देशों के उलट जब विधान परिषद के सदस्यों को वोट डालने की अनुमति देने के मुद्दे पर चर्चा की अपील की गई तो गौडा गुट बैठक से बाहर निकल आया. जब उन्होंने बैठक में लौटने से इनकार कर दिया तो गुप्त मतदान हुआ. हेगड़े के पक्ष में 109 वोट पड़े, 42 विरोधी विधायक गैरहाजिर रहे.

हेगड़े की जीत से असंतुष्ट खेमे का मनोबल गिर गया था और उसमें घबराहट फैल गई थी. क्षुब्ध गौडा ने परस्पर विरोधी बयान जारी किए कि वे "जपा विधायक दल के फैसले का सम्मान करेंगे." लेकिन यह पूछे जाने पर कि क्या वे इस फैसले की वैधता मंजूर करते हैं, उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की. लेकिन एक प्रमुख असंतुष्ट नेता एम.एस. नारायण राव इन घटनाओं से अविचलित दिखे. वे कहते हैं, "मतदान उचित ढंग से नहीं हुआ. हम लड़ाई जारी रखेंगे."

गौडा गुट में शामिल असंतुष्टों की हेगड़े से खफा होने की वजह कमोबेश एक-सी है. गौडा के समर्थन का आधार सांप्रदायिक है, 42 में से 22 असंतुष्ट वोक्कलिग हैं (गौडा भी इसी समुदाय के हैं). दूसरे लोगों को भी हेगड़े से अपने हिसाब चुकता करने हैं.

गौडा को शुरू से ही हेगड़े विरोधी माना जाता रहा है. लगभग तीन वर्षों से कट्टर असंतुष्ट कई मुद्दों को लेकर अभियान चलाए हुए हैं. उनकी शुरुआती शिकायत हेगड़े के "भ्रष्ट, अहंकारी और अक्षम मंत्रियों" के खिलाफ थी. हेगड़े के विशालकाय मंत्रिमंडल; राज्य में चुनावी वायदों का पूरा न होना; बिजली की दरों में वित्तीय घपलेबाजी; दुगनी वृद्धि (जिससे मध्यम वर्ग बुरी तरह प्रभावित हुआ); शराब के उद्योगपतियों से पार्टी के लिए चंदा लेना; कैपिटेशन फीस लेने वाले कॉलिज; जमीन के घपले वाले सौदे और महत्वपूर्ण पार्टी मामलों पर जपा विधायक दल के सदस्यों के प्रति हेगड़े के उपेक्षा वाले

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रवैये से भी असंतुष्टों को शिकायतें थीं.

इसके उलट हेगड़े के वफादार असंतुष्टों के 'तुमसे बेहतर हम' वाले रवैये की हंसी उड़ाते हैं और कहते हैं कि असंतुष्ट खुद संदिग्धता से परे नहीं हैं. मिसाल के तौर पर प्रमुख असंतुष्ट एन.एस. हंबरवाडी के परिवार की बेलगांव में एक फाउंड्री है और उस पर बिजली चोरी का आरोप है. देवगौडा भी कर्नाटक पुलिस की जांच का सामना कर रहे हैं. उन पर भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और पद के दुरुपयोग के आरोप हैं.

जनता विधायक दल की हाल की बैठक से संकट तो दूर नहीं हुआ, असंतुष्टों के हौसले पहले से बुलंद जरूर हुए. हेगड़े को हटा न सकने पर अब वे राष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि बिगाड़ने की हरचंद कोशिश कर रहे हैं.

पिछले पखवाड़े शुरू हुआ विधानसभा सत्र दिलचस्प होगा क्योंकि कई पूर्व मंत्रियों ने हेगड़े सरकार की कलई खोलने का इरादा बनाया हुआ है. हेगड़े अनुशासनहीनता से कड़ाई से निबटने पर आमादा दिखते हैं. वे 28 मार्च को पार्टी के अधिकृत राज्यसभा उम्मीदवार के खिलाफ पाला-बदल मतदान करने वाले 10 विधायकों को निलंबित करने पर विचार कर रहे हैं. लेकिन गौडा भी सावधानी से चालें चल रहे हैं. हेगड़े की योजनाओं के बारे में पूर्वानुमान लगाते हुए वे कहते हैं, "सरकार का समर्थन तो आपसी समझ-बूझ पर निर्भर करता है."

हेगड़े को फूंक-फूंककर कदम रखने होंगे. उनके गुट के कम-से-कम 25 विधायक जिधर पलड़ा भारी दिखे उधर छलांग लगा सकते हैं कइयों को कमाऊ पद देने का लालच दिया गया है और अगर ये वायदे पूरे नहीं हुए तो वे दूसरे पाले में जा सकते हैं. यह हेगड़े के लिए अनिष्टकारी साबित होगा क्योंकि गौडा को जपा विधायक दल के एक-तिहाई से कुछ ही कम विधायकों का समर्थन हासिल है. एक-तिहाई समर्थन मिल जाने पर वे पार्टी तोड़कर विधानसभा में अलग बैठ सकते हैं. विधानसभा में असंतुष्टों और इंका के कुल मिलाकर 109 विधायक हैं जबकि हेगड़े के पास इससे कम विधायक हैं. जनता सरकार के गिरने के नौ साल बाद लगता है इतिहास फिर अपने को दोहराने जा रहा है. उस समय मोरारजी देसाई की सरकार को असंतुष्टों ने चुनौती दी थी. अब हेगड़े पर वैसा ही दबाव पड़ रहा है.

—अनीता प्रताप

आर.एल.जलप्पा

रशीद का भूत

लगता है पिछले कुछ हफ्तों से राम-कृष्ण हेगड़े के सारे ग्रह गड़बड़ा गए हैं. पिछले पखवाड़े जनता विधायक दल की बैठक में असंतुष्टों पर फतह हासिल करने के कुछ ही दिन बाद उन्हें अपने वफादार गृहमंत्री आर.एल. जलप्पा की विदाई का सदमा सहना पड़ा. रशीद हत्याकांड के मामले में ऐसा नाटकीय मोड़ आया कि जलप्पा के लिए गृहमंत्री की कुर्सी जलते तवे की तरह हो गई. किसी हत्याकांड में नाम उछलने के कारण इस्तीफा देने वाले किसी राज्य के वे पहले गृहमंत्री हैं.

जलप्पा के राजनैतिक पतन का रास्ता तो पिछले अगस्त में ही खुल गया था जब केरल के एक वकील एच.ए. रशीद की रहस्यमय हत्या के बाद राज्य के वकीलों ने हड़ताल कर दी थी. हालांकि रशीद की लाश तमिलनाडु में मिली पर वे दो दिन पहले ही बंगलूर के एक पुलिस स्टेशन पर देखे गए थे. शहर में एक निजी कॉलेज चलाने वाले पी. सदाशिवम के वकील की हैसियत से वे वहां गए थे.

पूर्व गृहमंत्री के आलोचकों के मुताबिक सदाशिवम इस वजह से जलप्पा के कोप-भाजन बन गए क्योंकि वे कोलार में एक निजी मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी कर रहे थे जबकि जलप्पा यह काम खुद करना चाहते थे. इंका नेताओं का आरोप है कि चूंकि रशीद कर्नाटक में अपने मुवक्किल के हितों की जोरदार तरीके से पैरवी कर रहे थे इसलिए सीधे गृहमंत्री के आदेशों से काम करने वाली स्थानीय पुलिस ने उन्हें ठिकाने लगा दिया. हालांकि वकील जलप्पा को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग कर रहे थे लेकिन हेगड़े ने मांग नहीं मानी और हत्या की जांच का काम केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के सुपुर्द कर दिया.

पहले छह महीने तक सीबीआई कुछ भी

मुश्ताक अहमद

जलप्पा: संकट में

करती नहीं दिखी. लेकिन पिछले महीने हेगड़े को पार्टी असंतुष्टों से चुनौती मिलते ही यह केंद्रीय एजेंसी एकाएक सक्रिय हो उठी. उसने आधा दर्जन से भी ज्यादा पुलिस वालों को गिरफ्तार कर लिया और उन पर रशीद की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया. स्वाभाविक रूप से हेगड़े को सीबीआई के अचानक हरकत में आने में कोई दूसरा ही उद्देश्य नजर आया. जलप्पा ने भी इस्तीफे से कुछ दिन पहले कहा था कि यह "मुझे राजनैतिक तौर पर खत्म करने का कांग्रेसी षड्यंत्र" है.

पर सीबीआई अपना मकसद हासिल करने पर अटल थी. उसने वरिष्ठ पुलिस अफसरों से पूछताछ की. जलप्पा से भी सवाल-जवाब किए. आखिर सीबीआई वालों ने पुलिस उपायुक्त के. नारायण को गिरफ्तार कर लिया. इससे यह अटकलें लगाई जाने लगीं कि अगला नंबर गृहमंत्री का है. जलप्पा फौरन अग्रिम जमानत के लिए अदालत जा पहुंचे. जमानत उन्हें दो दिन के लिए इस शर्त पर मिली कि वे शहर नहीं छोड़ेंगे यानी वे गृहमंत्री का दायित्व नहीं निभा सकते थे. इसके तुरंत बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया. बाद में उन्होंने स्थायी जमानत मांगी पर अदालत ने उनकी अर्जी खारिज कर दी.

जलप्पा के हटने से न सिर्फ पस्त जनता असंतुष्टों के हौसले बुलंद हुए बल्कि कर्नाटक में विपक्ष को भी पहले से ही विभाजित सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ नया हथियार मिल गया. प्रदेश इंका अध्यक्ष जनार्दन पुजारी का आरोप है, "हेगड़े की सरकार कातिलों की सरकार है और इसे तुरंत हटा दिया जाना चाहिए." हाल ही में बने जनता विधायक मंच (असंतुष्ट विधायकों के गुट) ने भी हेगड़े पर हमला बोल दिया. वैसे मंच ने जलप्पा के इस्तीफे को जनता पार्टी की लाज बनाने वाला बताया.

मामले का फैसला होने में कुछ साल तो नहीं पर कुछ महीने जरूर लग जाएंगे और तब तक रशीद का भूत हेगड़े और जलप्पा को सताता रहेगा.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

यूएनआई

घायल बीमार को ले जाते जवान

जम्मू

हौलनाक हादसे से हड़कंप

बच्चों का अस्पताल जमींदोज, दूसरी इमारतें भी खतरे में

पिछले पखवाड़े जम्मू और उसके इर्दगिर्द के कठुआ, उधमपुर और राजोरी जिलों में दो दिन का पूर्ण बंद स्वतःस्फूर्त ही था. लोग जम्मू मेडिकल कॉलेज बच्चों के अस्पताल की इमारत अचानक ढह जाने का विरोध कर रहे थे. इस हादसे में कम-से-कम 10 बच्चे मारे गए और 25 घायल हो गए थे. हादसे का कारण घटिया सामान बताया जाता है.

इससे पहले पुंछ और डोडा जिलों में प्राइमरी स्कूलों की करीब 20 इमारतें गिर चुकी हैं. ये इमारतें केंद्र की आर्थिक सहायता वाली ग्रामीण विकास योजनाओं के तहत बनाई गई थीं. अब अंदेशा है कि इन योजनाओं के तहत बनी करीब 1500 स्कूल इमारतें घटिया निर्माण की वजह से किसी भी समय ढह सकती हैं. आरोप लगाए जा रहे हैं कि इन इमारतों के निर्माण के ठेके सत्तारूढ़ नेशनल कांफ्रेंस और इंका नेताओं के करीबी ठेकेदारों को दिए गए थे.

इन आरोपों से राज्य सरकार विकट स्थिति में फंस गई है. जम्मू के स्थानीय अखबार मुख्य सरकारी निर्माण एजेंसी, जम्मू-कश्मीर परियोजना निर्माण निगम (पनिनि) की आपराधिक लापरवाही के खिलाफ प्रेस वक्तव्यों से भरे पड़े हैं. पिछले साल भी इस निगम द्वारा निर्मित एक शॉपिंग कांपलेक्स एक मंत्री द्वारा उद्घाटित किए जाने के कुछ हफ्ते पहले भरभराकर गिर गया था.

2 मई को हुआ हादसा और भी भयंकर होता यदि डॉ. महेश गुप्ता समय रहते कार्रवाई न करते. वे रात में ड्यूटी पर थे. करीब छह बजे सुबह गुप्ता को अस्पताल की तीसरी मंजिल की दीवार पर चौड़ी होती एक दरार दिखाई दी. उन्होंने तुरंत वह मंजिल खाली कराने का आदेश दिया. गुप्ता अस्पताल के दूसरे दो वार्डों तक पहुंचते, तब तक बहुत देर हो चुकी थी. इमारत का एक हिस्सा तत्काल मलबे में बदल गया और 50 से अधिक बच्चे, उनके रिश्तेदार और अस्तपताल के कर्मचारी उसके नीचे दब गए.

मौतों की सही तादाद के बारे में कुछ कहना मुश्किल है क्योंकि अस्पताल में दाखिल रोगियों का सारा रिकार्ड तीन सदस्यीय जांच आयोग के हवाले कर दिया गया है. हाईकोर्ट के सेवानिवृत न्यायाधीश इकबालकृष्ण कोतवाल की अध्यक्षता में इस आयोग को मुख्यमंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने नियुक्त किया. आयोग अपनी रिपोर्ट एक महीने के भीतर पेश करेगा.

मंडल आयुक्त एन.आर. गुप्ता के अनुसार इस इमारत में ढह जाने की 'तकनीकी वजहें' हैं. वे कहते हैं, "हो सकता है पिछली रातों को हुई भारी बारिश से नींव धंस गई हो." चार साल पहले इसका निर्माण पूरा हुआ. पर राज्य सरकार के एक इंजीनियर के मुताबिक नींव पुख्ता किए बिना ही इस पर दो मंजिलें और चढ़ा दी गई. इसके निर्माण का ठेका पहले कस्तूरीलाल गुप्ता को दिया गया जो हादसे के बाद फरार हो गए.

हादसे के बाद जम्मू के वकीलों के मंच ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके सभी सार्वजनिक इमारतों का निरीक्षण विशेषज्ञों की एक समिति से कराने की मांग की. मंच के प्रवक्ता और वरिष्ठ एडवोकेट श्यामसुंदर लहर ने आरोप लगाया कि मेडिकल कॉलेज के इ.एन.टी. विभाग, सार्वजनिक बस अड्डा, विश्वविद्यालय के नए परिसर और जिला अदालत समेत दर्जन भर से अधिक दूसरी इमारतें 'असुरक्षित' हैं.

स्थानीय अधिकारियों ने निवारक कदम उठाकर असंतोष पर काबू पाने की कोशिश की. जम्मू हादसे के एक हफ्ते के भीतर ही पुंछ जिले में 40 बिस्तरों वाले अस्पताल के शल्य चिकित्सा वार्ड से रोगियों को हटा लिया गया. पनिनि के बनाए इस अस्पताल के भी ढह जाने का अंदेशा है. इसके साथ ही अधिकारियों ने शहर के सार्वजनिक बस अड्डे की ओर भी ध्यान दिया. इस इमारत की नींव तभी से नाले के पानी में डूबी चली आ रही है जब 10 साल पहले पनिनि ने इसका निर्माण किया था.

पर सरकारी अधिकारी हादसे के बारे में चुप्पी साधे हुए हैं. इसकी वजह वे मामला जांच के लिए सुपुर्द कर दिया जाना बताते

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

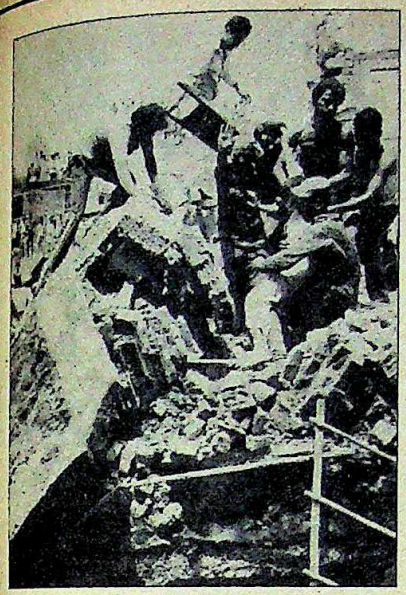

मलबे के पास राहत और बचाव

हैं. लेकिन लोग उससे संतुष्ट नहीं. उनका मानना है कि सबूतों के अभाव में दोषी शायद सजा से बच जाएं. जम्मू के एक युवा वकील रवींद्र शर्मा सवाल उठाते हैं, "अगर सरकार दोषियों को ढूंढ़ निकालने के प्रति गंभीर है तो उसने जांच का काम सीबीआई के बजाय आयोग को क्यों सौंपा?" पिछले पखवाड़े के हादसे को लेकर इतनी व्यापक प्रतिक्रिया इस बात का संकेत है कि यदि जांच अपूर्ण रही तो इमारतों के बजाय सत्तारूढ़ गठजोड़ की नींव को ही ज्यादा खतरा होगा.

—विपुल मुद्गल, जम्मू में

बिहार

खतरा बरकरार

बाढ़ फिर तबाही मचा सकती है

मानसून से पहले की बारिश ने पिछले पखवाड़े राज्य के उत्तरी जिलों को तरबतर कर दिया. इससे आठ महीनों पहले आई विनाशकारी बाढ़ की याद ही ताजा हुई. लगा कि फिर वही दर्दनाक कहानी दुहराई जा सकती है.

पिछले साल मचे जलप्रलय में 2,000 जीवन छिन गए (अधिकारी केवल 1,100 मौतों की बात स्वीकार करते हैं) और 20 लाख परिवार बेघर हो गए. बाढ़ का कहर राज्य के 39 में से 30 जिलों पर बरपा हुआ था. इसने लगभग 1,200 करोड रुपए की जायदाद मटियामेट कर दी और 3,400 किलोमीटर लंबे तटबंधों में 175 दरारें डाल दीं. 10,000 एकड़ से ज्यादा के खेत रेत से ढक गए. यह जमीन अब तक हल चलाने लायक नहीं हो पाई है. लगभग एक लाख लोग राजमार्गों और तटबंधों पर डेरा डाले पड़े हैं.

अकेले मधुबनी जिले के उपमंडल झंझारपुर में ही करीब 300 एकड़ जमीन घुटनों से लेकर कमर तक रेत से दबी हुई है. और मकान भी आधे हिस्से तक रेत में दब गए हैं. सतघड़ा गांव में चार एकड़ जमीन के मालिक 50 वर्षीय विश्वनाथ झा ने कहा, "इस जमीन पर हम पांच भाइयों के परिवारों का गुजारा चलता था लेकिन अब हम कंगाल हो गए हैं." हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे ने बाढ़पीड़ितों के पुनर्वास का आश्वासन दिया था पर बावजूद इसके बदहाली बरकरार है.

कुछ जिलों का दौरा करके लौटे नए मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद ने कहा, "नहीं, कुछ भी नहीं किया गया." आजाद ने दौरे के बाद अफसरों को राहत कार्यों में कोई कोताही न बरतने का आदेश दिया. उन्होंने नष्ट हुए तटबंधों की मरम्मत का काम मई के अंत तक पूरा करने का भी फरमान जारी किया.

लेकिन चालाक ठेकेदारों और अफसरों को मरम्मत का 'तरीका' पता है. तटबंधों की दरारें सिर्फ रेत से ही भर दी जाती हैं. झंझारपुर के आदलपुर तटबंध में पिछले साल छह दरारें पड़ीं और उन्हें भरने का काम एक ही ठेकेदार को दिया जाता रहा. हाल में जब आजाद ने उस स्थान का दौरा किया तो उन्होंने चेतावनी दी, "यदि इस तटबंध में दुबारा कटाव हुआ तो ठेकेदारों और इंजीनियरों को इसमें डूबना पड़ेगा."

विलासपुर-हायाघाट (आबादी: 3,600) गांव में जो कुछ गुजरा उसकी तो कल्पना करके ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं. कारे नदी के तट पर बसे इस गांव की हिफाजत मिट्टी और ईंटों से बने बांध करते थे. पिछले साल 13 अगस्त की रात बाढ़ ने 31 लोगों को लील लिया और 85 घर कीचड़ से ढक गए. जहां कभी मकान हुआ करते थे आज वहां पोखर दिखाई देता है.

बाढ़पीड़ितों को वायदे भरपूर मिले—घर बनाने में सहायता के, पुनर्वास के और मुफ्त भोजन देने के भी. लेकिन आखिर में केवल 177 लोगों को घर बनाने के लिए 200 रु. प्रति व्यक्ति के हिसाब से थमा दिए गए. 55 वर्षीय भूमिहीन मजदूर सुभान ने कहा, "यह तो जले पर नमक छिड़कने जैसा है." यह अत्यल्प राशि भी एकमुश्त नहीं दी गई. इस सहायता राशि में कटौती की वजह के बारे में पूछने पर दरभंगा के मंडल आयुक्त जी. कृष्णन ने कहा, "हम सरकार की समझदारी पर सवाल नहीं उठाते. हम तो सिर्फ फैसले लागू करते हैं." 5.5 करोड़ रु. की गृह निर्माण की अनुदान राशि मांगे जाने पर केवल 1.5 करोड़ रु. ही उपलब्ध कराए गए.

यही कहानी मधुबनी जिले की है. जिलाधिकारी बी.बी. श्रीवास्तव के अनुसार 2.38 लाख घरों को नुकसान पहुंचा या वे नष्ट हो गए. सहायता राशि देने के लिए 4.75 करोड़ रु. की जरूरत थी. लेकिन सरकार ने 1.28 करोड़ रु. ही स्वीकृत किए. यहां तक कि सड़कों की मरम्मत के लिए केवल 54 लाख रु. आबंटित किए गए. कार्यकारी अभियंता (सड़क) जी.एन. सिन्हा के मुताबिक यदि कम-से-कम 72 लाख रु. तुरंत उपलब्ध नहीं कराए गए तो अगली बारिश के दौरान सभी सड़कें आवाजाही के लायक नहीं रह जाएंगी.

पहले जहां बस्ती थी, आज पोखर है: कहर का असर कायम

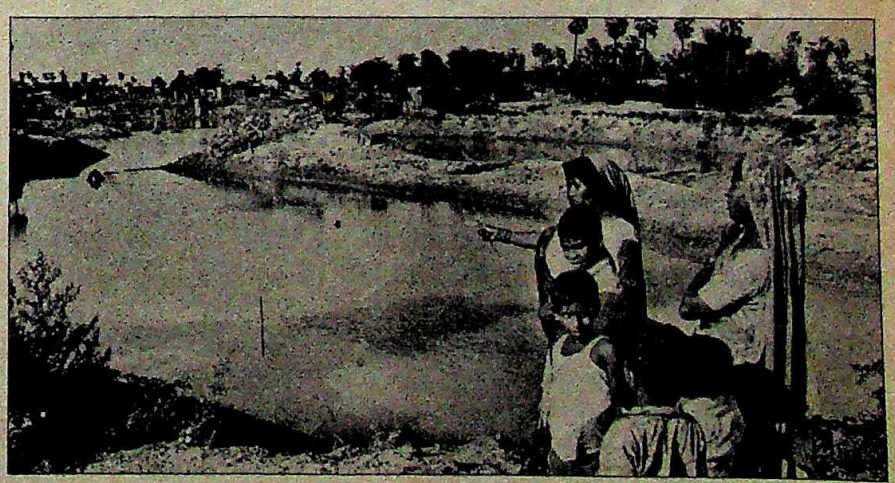

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पर बाढ़पीड़ितों की सहायता और पुनर्वास पर 140 करोड़ रु. खर्च करने का दावा करने वाली दुबे सरकार के लिए रकम की कमी जैसी कोई समस्या नहीं थी. लेकिन इस दावे की पोल उस वक्त खुल गई जब जनता पार्टी के नेता रघुनाथ झा ने आरोप लगाया कि सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए 85 करोड़ रु. में से 15 करोड़ रु. का भी इस्तेमाल नहीं किया.

हालांकि आजाद ने अगले मानसून की तैयारी के लिए जिलाधिकारियों को खुली छूट दे रखी है. लेकिन बिहार में दूसरे मानसून की दस्तक के साथ ही लोगों का प्रशासन में फिर विश्वास स्थापित करना मुश्किलों भरा होगा. —फरजंद अहमद

बिहार

मुक्ति अभियान

बड़े अफसर इधर से उधर

हालात अब पहले जैसे नहीं हैं. भागवत झा आजाद के मुख्यमंत्री बनने के तीन महीने बाद ही बिहार में बदलाव आने लगा है. वे यह साबित करने पर तुले दिखते हैं कि नए होने के बावजूद वे अलग किस्म के हैं और उनकी कार्रवाइयों का मकसद कार्यकुशलता का माहौल तैयार करना है.

उन्होंने राज्य की दुखती रग पर हाथ रख दिया है. मुख्यमंत्री ने सरकारी अफसरों के अमले में इस तरह उलटफेर किया है कि वे तमाम क्षेत्रीय और जातीय समीकरण गड़बड़ा गए हैं जिन्होंने वर्षों से प्रशासन को अपने नागपाश में बांध रखा था. आजाद कहते हैं, "मेरी कोशिशें प्रतिभा पहचानने और बेहतरीन अफसरों को महत्वपूर्ण पदों पर बिठाने की हैं ताकि वायदे पूरे हो सकें. मैंने क्या कोई अनोखा काम किया है?"

पर मानव संसाधन विकास आयुक्त अरुण पाठक को अतिरिक्त मुख्य सचिव पद पर बिठाकर उन्हें गृह (पुलिस और अपराध जांच समेत), 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन, राहत और पुनर्वास विभाग देना ज्यादातर अफसरों को अनोखा ही लगा है. इसके अलावा उन्हें एस.के. चतुर्वेदी की जगह मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव का काम अंजाम देने को भी कहा गया है. चतुर्वेदी ने दिल्ली तबादला करा लिया है. सत्ता और अधिकार के इस अनोखे मिलन से पाठक राज्य की नौकरशाही में न सिर्फ दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं बल्कि इससे मुख्य सचिव आर. श्रीनिवासन की हैसियत महज कागजी बनकर रह गई है.

सही है कि पाठक की छवि एक ईमानदार अफसर की है पर तरक्की दिए जाने की प्रक्रिया में वे कम-से-कम 15 दूसरे अफसरों को लांघ गए हैं. मगर मुख्यमंत्री के नजदीकी सूत्र इसका खंडन करते हैं. उनका कहना है कि किसी अफसर की वरीयता लांघने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि इससे आईएएस अफसरों के वेतनक्रम और वरिष्ठता पर कोई असर नहीं पड़ा. आजाद कहते हैं, "किस अफसर को कहां तैनात किया जाए यह तय करना मुख्यमंत्री का अधिकार है."

पाठक की तरक्की इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि आजाद से पहले बिंदेश्वरी दुबे के शासनकाल में पाठक को अहम ओहदों से दूर ही रखा जाता रहा. उन्हें दुबे और उनके असरदार प्रधान सचिव के.ए. एच. सुब्रमण्यम के हाथों अपमान भोगना पड़ा. पाठक ने यह परेशानी खुद ही मोल ली थी क्योंकि वित्त आयुक्त की हैसियत से उन्होंने फालतू खर्चों का विरोध किया था और वित्तीय गड़बड़ियों के कई मामलों का पता लगाया था.

दुबे के ही शासनकाल में अफसरों का एक गुट नौकरशाही पर हावी हो गया था. इसमें सुब्रमण्यम की अहम भूमिका के चलते मुख्यमंत्री का सचिवालय सारी सत्ता का केंद्र बन गया था. पद संभालने के तुरंत बाद आजाद ने कई दूसरे अफसरों की मौजूदगी में सुब्रमण्यम से बड़ी रुखाई से साफ-साफ कह दिया था कि उन्हें मौजूदा पद पर नहीं रहने दिया जाएगा.

फिर आजाद ने मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस अफसर जे.एम. कुरेशी को राज्य का पुलिस महानिदेशक बनाकर पूरे पुलिस विभाग को ही हक्का-बक्का कर दिया. पर कुरेशी ने सभी वरिष्ठ पुलिस अफसरों को व्यवहारकुशलता से विश्वास में लेकर तनाव ठंडा किया. अब पाठक भी उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां वे कुरेशी से तालमेल बिठाकर पुलिस विभाग में सफाई अभियान चला सकते हैं. पुलिस महानिदेशक ने गृह विभाग की अनदेखी कर पुलिस के लिए कुछ योजनाओं की मंजूरी सीधे मुख्यमंत्री से लेकर हलचल मचा रखी है.

आजाद ने महज सुब्रमण्यम के गुट को ही तोड़ने की कोशिश नहीं की, उन्होंने पी.के. मिश्र की जगह वित्त सचिव पद पर एक प्रतिष्ठित आईएएस अफसर मुकुंद प्रसाद को

अफसरों के अमले में इस तरह उलटफेर किया गया है कि वे तमाम क्षेत्रीय और जातीय समीकरण गड़बड़ा गए हैं जिन्होंने वर्षों से प्रशासन को अपने नागपाश में बांध रखा था

पाठक

श्रीनिवासन

कुरेशी

भी नियुक्त किया. मिश्र का कामकाज बेहतर नहीं माना जाता था इसलिए उन्हें स्वास्थ्य विभाग की कमान थमा दी गई. खनन आयुक्त एम.एल. मजूमदार को एन.के. अग्रवाल की जगह कार्मिक सचिव के महत्वपूर्ण पद पर लाया गया. वन आयुक्त सी.आर. वेंकटरामन को जल संसाधन विकास जैसे महत्वपूर्ण विभाग का सचिव बना दिया गया जबकि स्वास्थ्य आयुक्त बी.बी. लाल को नए राजस्व और भूमि सुधार विभाग में आयुक्त के पद पर बिठाया गया. इंका नेता कमलनाथ सिंह ठाकुर कहते हैं, "बहुत से महत्वपूर्ण पदों के लिए काबिल अफसरों को चुनकर आजाद ने प्रशासन में नई जान फूंकी है."

पर लगता है अफसर सबसे ज्यादा कुरेशी, मुकुंद प्रसाद और मजूमदार को लेकर विचलित हैं क्योंकि वे नौकरशाही के जातीय समीकरण पर पूरे नहीं उतरते. मुख्यमंत्री के नजदीकी सूत्रों का कहना है कि अभी ऐसी कई कार्रवाइयां हो सकती हैं. इस बात की भी काफी संभावना है कि केंद्र में प्रतिनियुक्त बिहार कैडर के कई अफसर जल्द ही राज्य में लौट आएं.

पर ऐसे सुनियोजित झटकों से क्या सचमुच किसी सुधार की संभावना है? गद्दी संभालने के तुरंत बाद पहले भी कई मुख्यमंत्री ऐसी कोशिशें कर चुके हैं पर उन्हें मनमुताबिक परिणाम नहीं प्राप्त हुए. इसलिए हालात अगर बेहतर न हुए तो मुख्यमंत्री आजाद की नौटंकी भी बेकार सिद्ध हो सकती है. —फरजंद अहमद

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मध्य प्रदेश

पराक्रमी पुलिस

खूब भांजी हवा में लाठी

मध्य प्रदेश में हवालात में होने वाली मौतों, बलात्कारों और फर्जी मुठभेड़ों की वजह से यहां की पुलिस खासा नाम कमा चुकी है. पर हाल ही में राज्य के पुलिस विभाग ने जिस कुशलता से 'हत्या' की एक गुत्थी सुलझाई और 'हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों' से 'इकबालिया' बयान हासिल किया उससे उसकी कुशलता के सारे रिकार्ड टूट गए. कारण—दरअसल कोई हत्या हुई ही नहीं थी.

हुआ यह कि होशंगाबाद जिले के एक गांव में मिलावट संबंधी एक मामले में वारंट देने के लिए हवलदार विनय दुबे गया और लौटकर नहीं आया. लिहाजा दाल में काले की आशंका से त्रस्त पुलिस ने जांच शुरू की और देखते-देखते हत्या का मामला दर्ज किया, दो लोगों से हत्या का इकबालिया बयान लेने के साथ-साथ हत्या का एक 'चश्मदीद' गवाह ढूंढ़ लेने की घोषणा भी कर डाली. मगर वाह री (पुलिस की) किस्मत. जिस दिन दोनों 'हत्यारों' को जेल में डाला गया ठीक उसी दिन 'मृत' हवलदार 'जीवित' हो उठा.

इस कांड से राज्य भर में रोष की लहर दौड़ गई. पिछले पखवाड़े इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने वाले भाजपा विधायक बाबूलाल गौड़ की टिप्पणी थी, "इस बात की कल्पना की जा सकती है कि एक ऐसी हत्या के लिए जो हुई ही नहीं, किस दर्जे के हथकंडे इस्तेमाल किए गए होंगे."

आतंक और भय का यह नाटक 6 अप्रैल को शुरू हुआ जब दुबे पिपराला थाना से 6 किलोमीटर दूर बुधनी गांव के लिए साइकिल पर रवाना हुआ. दारू के नशे में वह मामले से जुड़े दोनों अभियुक्तों अशोक दीक्षित और उसके भाई फूलचंद समेत गांव के कुछ युवकों से जा भिड़ा. इस तकरार में उसकी जमकर पिटाई हुई और वह अपनी साइकिल और डंडा छोड़ भाग खड़ा हुआ.

उसके बाद थाने वालों को अगले 6 दिन तक दुबे की कोई खबर नहीं मिली. मानवाधिकार संगठन पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) की ओर से मामले की जांच करने के लिए वहां गई टीम की मुखिया सुधा सक्सेना ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है: "दुबे नशे में था और ऐसी आशंका है कि वह अपने खिलाफ गांववालों की रिपोर्ट से डरते हुए थाने नहीं गया."

घटना के दो दिन बाद पुलिस ने अपने सहयोगी की खोज का अभियान शुरू किया और 8 से 12 अप्रैल के बीच बीसियों ग्रामीणों को जवाबतलब के लिए थाने बुलाया गया. इनमें से 5 महिलाओं और 11 बच्चों समेत लगभग 50 लोगों को 5 दिन के लिए थाने में ही रोके रखा गया. डंडों और लाठियों के इस्तेमाल के अलावा उन्हें सुइयां चुभोने और भूखा-प्यासा रखने जैसे हथकंडे इस्तेमाल किए गए.

इसी दौरान 9 अप्रैल को पुलिस ने नदी के किनारे कटी हुई एक टांग बरामद हुई जिसे दुबे की टांग घोषित करते हुए हत्या का मामला दर्ज किया गया. अपराध विज्ञान प्रयोगशाला ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि टांग तीन महीने पुरानी थी.

पुलिस ने जिस कुशलता से 'हत्या' की गुत्थी सुलझाई और जिम्मेदार लोगों से इकबालिया बयान लिया उससे सारे रिकार्ड टूट गए. दरअसल हत्या हुई ही नहीं थी

(ऊपर से) रामबाई, नरेश और सुखदेव दुबे

पुलिस दीक्षित परिवार पर शक कर रही थी. जांच के दौरान दीक्षित भाइयों की 70 वर्षीय मां रामबाई को भी नहीं बख्शा गया. उनका आरोप था, "उन्होंने मुझे नंगा कर दिया और मेरे गुप्तांगों में पिसी हुई मिर्च डाली." 10 वर्षीय तंतु उर्फ नरेश भी पुलिस की हद दर्जे की बर्बरता का शिकार हुआ. उसने अपनी घायल उंगली दिखाते हुए बताया, "उन्होंने चिमटी से मेरी एक उंगली का नाखून उखाड़ दिया." यह सब उसकी मां की आंखों के सामने किया गया ताकि वह बच्चे की चीख-पुकार सुन सके.

लेकिन सबसे बुरी हालत अशोक और फूलचंद की हुई. उन्हें 5 दिन तक लगातार पीटा गया—तब तक जब तक कि उन्होंने हार कर 'हत्या' का अपराध 'कबूल' नहीं कर लिया. सिर्फ इतना ही नहीं, इस हत्याकांड का एक 'चश्मदीद' गवाह 50 वर्षीय सुखदेव भी तैयार कर लिया गया.

इसके बाद 12 अप्रैल को राज्य पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल अरुण गुई ने संवाददाता सम्मेलन में विजयी अंदाज में घोषणा कर दी कि अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ मामला सुलझा लिया गया है. मगर अगले ही दिन 60 किमी दूर इटारसी में 'मृत' दुबे का चलता-फिरता भूत अपने एक रिश्तेदार के यहां प्रकट हो गया. उसका कहना था कि गांववालों ने उसे मार-पीटकर और बांधकर जंगल में डाल दिया था. वहां से वह मुश्किल से निकल भागा.

इस मामले में दोषी लोगों के खिलाफ कदम उठाने के बजाय बड़े अफसरों और राजनेताओं ने मामले को रफादफा करने की कोशिश की. भले ही हत्या का मामला वापस ले लिया गया पर गिरफ्तार लोगों की जमानत नामंजूर करने के साथ-साथ उन पर हवलदार को पीटने और उसे हिरासत में रखने का नया मामला भी दर्ज कर दिया गया.

पीयूसीएल की टीम और भाजपा द्वारा दखल दिए जाने और विधानसभा में विपक्ष द्वारा सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाए जाने के बाद सरकार ने रुख बदला. उसके बाद 3 मई को उच्चस्तरीय जांच करवाने और पुलिस अत्याचार के शिकार लोगों की मेडिकल जांच के आदेश जारी किए.

सवाल उठता है कि यदि हवलदार वापस न आता तो क्या होता? विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र शुक्ला के शब्दों में, "भगवान का शुक्र है कि पुलिस के सामने अभियुक्त के इकबालिया बयान को अदालत में कोई महत्व नहीं दिया जाता." —नरेंद्र कुमार सिंह

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आत्मनिर्भर हो गए हम

पिछले दिनों की बात है. अमेरिका के राजदूत जॉन गुंथर डीन भारत के दौरे पर आए थे. अक्सर उनके देश की आलोचना करते रहने वाले इस देश की तरक्की की रफ्तार देख वे चकित हुए. अंचभा मिश्रित हर्ष की अभिव्यक्ति वे कब तक रोक पाते. एक सेमीनार में उन्होंने अपने उद्गार व्यक्त कर ही डाले कि "भारत को बड़े आत्मविश्वास के साथ 21वीं सदी और आत्मनिर्भरता की ओर कदम" बढ़ाते देखकर वे भारत को मुबारकबाद दिए बिना रह नहीं सकते.

समाचार माध्यमों में यह खबर पढ़कर मैं उलझन में रहा कुछ दिन. लेकिन आखिर भारत सरकार के एक बड़े अधिकारी से पूछ ही बैठा, "साहब हमारा आयात जो है वह तो दिन-ब-दिन बढ़ता ही जा रहा है. तो भला ये राजदूत महोदय हमें 21वीं सदी और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के लिए बधाई कैसे दे रहे हैं?"

अधिकारी महोदय ने मेरी बात बड़े ध्यान और धैर्य से सुनी. फिर होंठों ही होंठों में मुस्कराए और बोले, "जनाब ऐसा है कि 21वीं सदी में आत्मनिर्भरता का पैमाना व्यापार संतुलन नहीं रह जाएगा. अमेरिकी राजदूत तो दरअसल राजीव गांधी को बधाई दे रहे हैं कि भारत को अब अमेरिका या रूस का मुंह ताकते नहीं रहना पड़ेगा. इन बड़ों ने हमारे लिए एक दिशा तय कर दी है और हम अपने भरोसे ही उधर बढ़ रहे हैं."

अधिकारी महोदय का जवाब मुझे कुछ जंचा नहीं, सो मैंने टोक दिया, "लेकिन साहब, राजीव राज में अमेरिका या रूस पर हमारी निर्भरता घटी है यह मुझे तो नहीं दिख रहा."

उन्होंने तुरंत समझाया, "आपकी समझ में क्यों नहीं आता कि तोड़फोड़ वगैरह के लिए हमें अब सीआईए या केजीबी की मदद नहीं चाहिए. यह सब अब हम खुद कर सकते हैं. रॉ को ही देखिए. वह किस तरह दनादन सिख आतंकवादियों को रॉकेट और तमिल छापामारों को बंदूकें मुहैया कराए जा रहा है. इन मामलों में तो हमें अब आयात की कोई जरूरत ही नहीं रह गई है."

मैं चीख पड़ा, "कितना खतरनाक है यह! विदेशी हमले हुए तो हम तो घुटने टेक देंगे श्रीमान! सारा देश एकदम बरबाद हो जाएगा!"

अधिकारी महोदय पर मेरी चीख का जैसे कोई असर ही नहीं हुआ. हंसते हुए वे

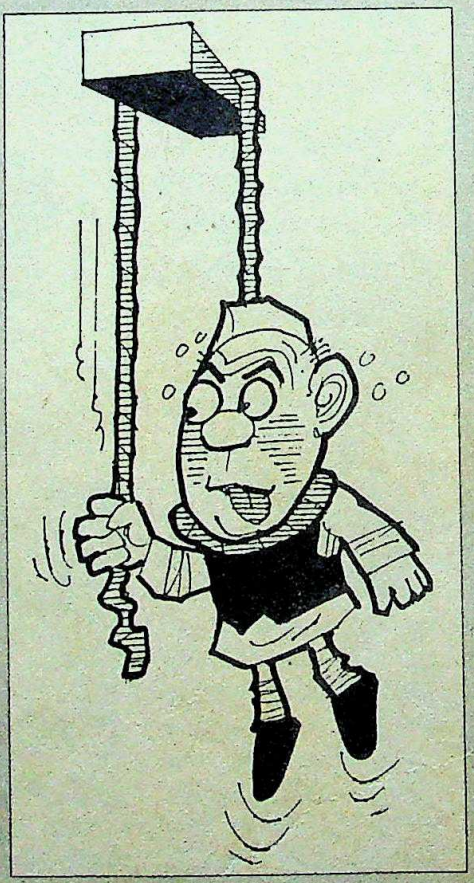

बोले, "अरे नहीं भाई! प्रधानमंत्री जी का शुक्र मनाइए कि अब ऐसी लड़ाई के लिए हमें विदेशी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी. पूरे स्वावलंबी हो गए हैं हम. चीन या पाकिस्तान की मदद के बिना अब हम सरकार द्वारा तैयार किए गए कई क्षेत्रों में पूरे पैमाने पर गृहयुद्ध कर सकते हैं. पंजाब, दार्जिलिंग, झारखंड, तमिलनाडु, कश्मीर, पश्चिम उत्तर प्रदेश कहीं भी थोड़े दिनों के नोटिस पर हम गृहयुद्ध तैयार कर सकते हैं."

मेरा धैर्य जवाब देने लग गया था. मैं गुस्से में बोल पड़ा, "लड़ाई के मामले में आत्मनिर्भरता का क्या फायदा? लड़ाई से बेमतलब हिंसा और मौत के सिवा क्या हासिल होगा?"

मुझे गुस्से में देखकर अधिकारी महोदय ने तुरंत पैंतरा बदला, "समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं, खुद अपनी बरबादी के लिए लड़ाई लड़ना तो पुराना और भौंडा तरीका है. इसलिए हमने नए तरीके इजाद करने के लिए अपना 'रिसर्च ऐंड एनालिसिस' (शोध व विश्लेषण) शुरू किया है. देश में अस्थिरता पैदा करने में हमने पूरी महारत हासिल कर ली है और फिर हमारा तरीका भी लड़ाई से ज्यादा आधुनिक और सुरक्षित है. कुछ समझे आप?"

मैंने सवाल किया, "इस मामले में हम आत्मनिर्भर कैसे हुए?"

"पूरी तरह देसी साधनों के बलबूते", अधिकारी महोदय ने जवाब दिया, "हमें अपने देश की अस्थिरता के लिए अब विदेशी ताकतों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं. बूटा सिंह, जैल सिंह, राजीव गांधी के बयान ही काफी हैं तमाम संस्थाओं और पूरी व्यवस्था को नाकाम कर देने के लिए."

अब मुझे उनकी बातों का मर्म कुछ-कुछ समझ में आने लगा था. सोचते हुए मैं बोला, "हूं...यानी आपका मतलब है कि आर्थिक व्यापार संतुलन भले गड़बड़ हो, 'राजनैतिक व्यापार' संतुलन बिलकुल दुरुस्त है."

"अरे भाई दुरुस्त ही नहीं, पलड़ा हमारी ओर झुक गया है", अधिकारी महोदय गर्व से बोले, "ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने से हम भ्रष्टाचार का आयात करते आ रहे थे. लेकिन अब इसकी कतई जरूरत नहीं रह गई है. भला हो बेचारे बोफोर्स और एचडीडब्ल्यू कंपनियों के साथ हुए सौदों का—आज हम इस हैसियत में पहुंच गए हैं कि दुनिया भर के देशों को भ्रष्टाचार का थोक पैमाने पर निर्यात कर सकते हैं."

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

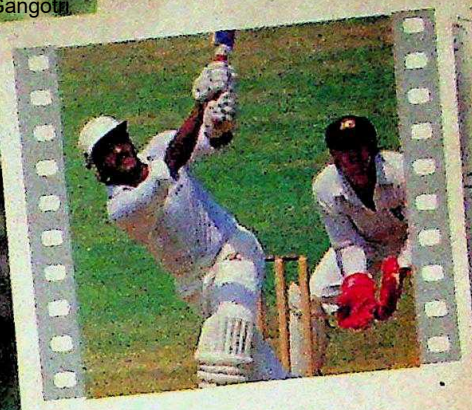

रवि का हर अंदाज़ अनोखा.

रवि शास्त्री. साहसी ऑल राउन्डर, जानी-मानी हस्ती, चुस्त फुर्तीले और सदा संवरे व्यक्तित्व के मालिक.

अब रवि ने पाली है मनपसंद सूटिंग— विमल सूटिंग. यहाँ आप पर सज रहे हैं— सामयिक ब्लूज़ाँ जैकेट, कोट-स्टाइल नॉच्ड लैपल, अनोखे कॉलर वाली लेमन येलो शर्ट और ऑफ़ व्हाइट पेंट- गर्मी की खुशगवार शामों के लिए.

VIMAL®
A RELIANCE PRODUCT

पॉलिएस्टर और
वूल ब्लेन्डिड सूटिंग्स

विजेताओं की शान!

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हवाओंमें
एक नई
कल

Domain, Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ाओंमें
एकनई महकती
हलचल!

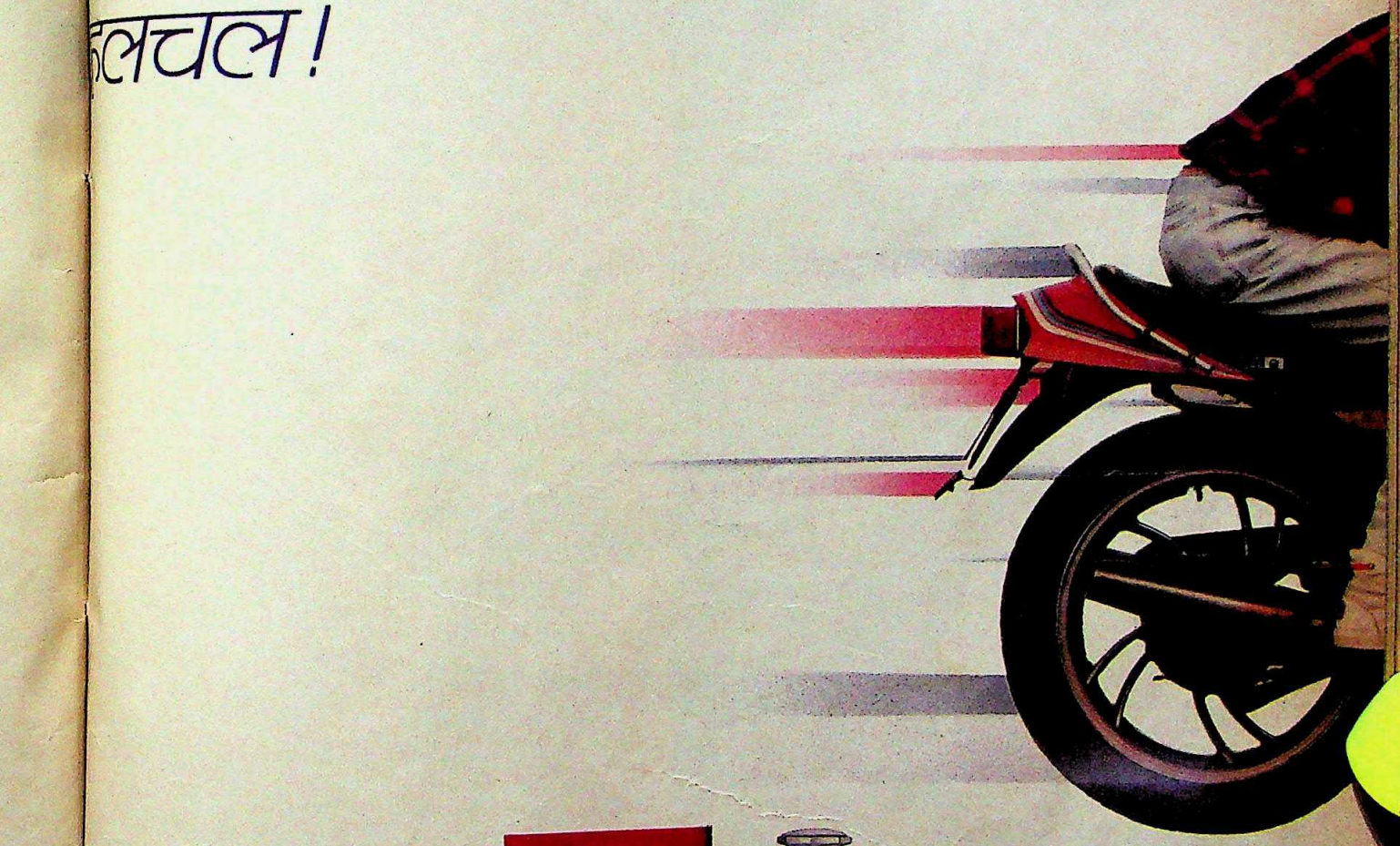

सनसनाती! महकाती! ठंडक और ताज़गी बरसाती मदमाती हलचल! ओल्ड स्पाइस आफ़्टर शेव लोशन के साथ.

सुगंध, जो देर तक आप से लिपटी रहे...
आप का सुगंधित परिचय बन जाए!
शेव के बाद... स्नान के बाद... किसी ख़ास बात से पहले... किसी मुलाकात से पहले, ओल्ड स्पाइस!

ओल्ड स्पाइस
मर्दानगी की मस्तानी महक

मि. ली. के पैक में. केवल १८.००* रु.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हिंदी फिल्मोद्योग

कभी शोले

भवान सिंह

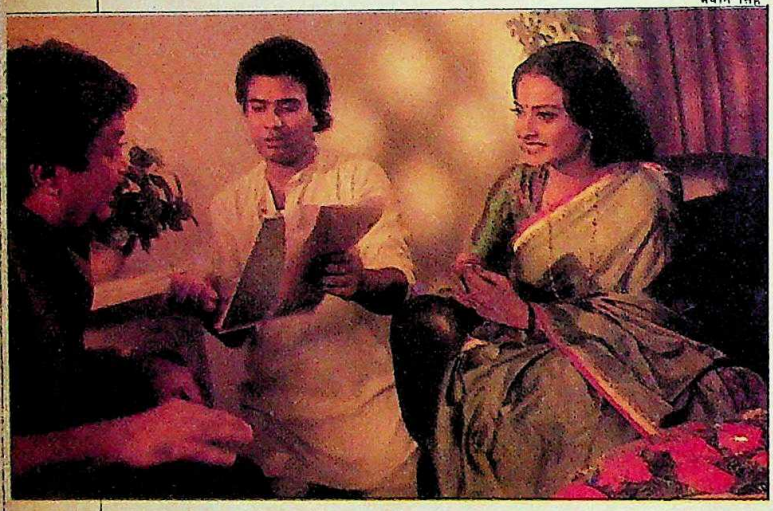

हालात इतने उलझन भरे हैं मानो चरित्रों और उप-कथानकों से भरपूर मारधाड़ वाली किसी फिल्म की पटकथा हो. इससे माहौल ज्यादा बोझिल ही हुआ है. भारतीय फिल्म उद्योग अगले महीने अपनी प्लैटिनम जुबली मनाने की तैयारी में जुटा है, साथ ही उथलपुथल के ऐसे दौर से भी गुजर रहा है जिसका सामना उसने अपने 75 साल के इतिहास में कभी नहीं किया था. अहंकार, अमर्यादित आचरण और खतरा मोल लेने की अंधी प्रवृत्ति के लिए मशहूर इस उद्योग के अनुभवी लोग भी नहीं जानते कि आगे क्या होगा. हिंदी सिनेमा में आज अराजकता का ही राज चल रहा है.

आंकड़े भी इसके दुर्भाग्य की ओर ही संकेत करते हैं. 1947 में भारत में बनी 281 फिल्मों में से 184 फिल्में हिंदी फिल्म जगत के सपने बुनने वालों की देन थीं. चालीस साल बाद यह अनुपात एकदम गड़बड़ा गया. 1987 में बनी 806 फिल्मों में हिंदी की 150 फिल्में ही थीं. लेकिन फिल्म स्टुडियो में संकट उतना गहरा नहीं जितना बाजार में है. हिंदी फिल्में अब न तो पहले की तरह बिक रही हैं, न मुनाफा दे रही हैं. पिछले साल बनी 150 फिल्मों में से वितरकों ने 100 ही फिल्में उठाईं, जो पूरे देश के सिनेमाघरों में दिखाई गईं. इनमें से 80 बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटीं. सिर्फ छोटे बजट की फिल्म *प्रतिघात* ही सफल रही. फिल्में पिटने से पिछले साल निर्माताओं को 50 करोड़ रु. का नुकसान हुआ. निर्माता और लेखक अमित खन्ना कहते हैं, "हम तेजी से उस मुकाम की ओर बढ़ रहे हैं जहां फिल्म व्यवसाय पूरी तरह धराशायी हो जाएगा. 1913 में दादा साहब फालके की *राजा हरिश्चंद्र* के साथ फिल्म व्यवसाय पनपना शुरू हुआ था और 1988 में इसमें मंदी का दौर शुरू हो गया है."

हालांकि 1987 में सिर्फ *प्रतिघात* ही बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही थी. लेकिन इसके बावजूद फिल्मोद्योग में दनादन पैसा लग रहा है. पिछले साल 783 फिल्मों के निर्माण की घोषणा की गई

लेकिन सिनेमा जैसा कोई दूसरा व्यवसाय है भी नहीं—खास तौर पर दूसरे उद्योगों का फालतू पैसा खपाने के मामले में. फिल्म व्यापार की साप्ताहिक पत्रिका 'बॉक्स ऑफिस' के संपादक उदयराव कवि के अनुसार ताज्जुब की बात यह है कि बड़े परदे पर फिल्मों के लगातार पिटने के बावजूद 1987 में 783 फिल्मों के निर्माण की घोषणा हुई. अनुमान है कि इस समय 400 फिल्मों का निर्माण चल रहा है.

(ऊपर) देवेन वर्मा (एकदम बाएं) के साथ रेखा सेट पर; *प्रतिघात* और *मि. इंडिया* के दृश्य

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कभी शबनम

हर एक की 75 लाख रु. औसत लागत के हिसाब से इन सभी फिल्मों की लागत कुल मिलाकर 300 करोड़ रु. बैठती है. लेकिन इनमें से सिर्फ एक-तिहाई के ही पूरा होने की संभावना है.

फिल्मोद्योग संकटग्रस्त है और इसमें अचानक उथलपुथल मच गई है. हिंदी सिनेमा हमेशा फिल्मोद्योग के बाहर से आए पैसे पर ही टिका रहा है. लेकिन 37 वर्षों से फिल्मों में पैसा लगाते आए और 13 वर्षों से उनके वितरण का धंधा कर रहे परिवार के बालकृष्ण श्रॉफ कहते हैं, "अब स्थिति बहुत नाजुक हो गई है. फिल्म निर्माण में तो वृद्धि हो रही है पर वितरण का काम मंदा है." फिल्म व्यवसाय पर नए फाइनांसरों का दबदबा भी पहले से बढ़ा है. वे अपने साथ नए, अनुभवहीन निर्माता और निर्देशक लाते जा रहे हैं.

फिर भी यहां चारों ओर से पैसा बरस रहा है. हीरों के धनी-मानी व्यापारी, दुबई के प्रवासी भारतीय और जमीन-जायदाद तथा सराफा बाजार के दलाल इस उद्योग में पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं. विडंबना यह है कि पहले हिंदी फिल्मों के चोरी-छिपे वीडियो कैसेट बनाकर बेचने से अमीर हुए लोग भी फाइनांसर बन गए हैं. पैसे की गरमार से निर्माता अनुबंध करने के लिए अब भी बॉक्स ऑफिस पर कामयाब मुट्ठी भर सितारों के आगे-पीछे घूमने लगे हैं.

हिंदी फिल्में न बिक रही हैं, न मुनाफा दे रही हैं फिर भी दर्शकों को बराबर परोसी जा रही हैं. पिछले साल थिएटर तक पहुंची 100 में से 80 फिल्में बड़े सितारे होने पर भी टिकट खिड़की पर बुरी तरह पिट गईं

लेकिन सितारे और स्टुडियो इतने व्यस्त हैं कि निर्देशक समय पर शूटिंग पूरी नहीं कर पा रहे, फिल्म निर्माण का स्तर घटा देने और तीन दिन की शूटिंग को एक दिन में पूरी कर लेने का इंतजाम करने पर भी नहीं. 1975 में शोले बनाकर इतिहास रचने वाले रमेश सिप्पी ने अब तक के सभी रिकार्ड तोड़ देने वाली इस फिल्म की शूटिंग करीब 350 दिनों में पूरी की थी. आज वे अमिताभ बच्चन को लेकर बना रहे अपनी ताजा फिल्म *अकेला* को 100 दिन की शूटिंग में ही पूरी कर लेने की उम्मीद कर रहे हैं. सिप्पी कहते हैं, "फिल्म शुरू करना तो आसान है पर बड़ी समस्या उसे पूरा करने की है. आज हर तरफ अराजकता है. फिल्मोद्योग अपने इतिहास के भयंकर उतार-चढ़ाव से गुजर रहा है." पिछले साल की सफल फिल्म *लोहा* के निर्देशक राज सिप्पी कहते हैं, "हम बहुत तेज रफ्तार से चल रहे हैं. मुझे आशंका है कि किसी दिन

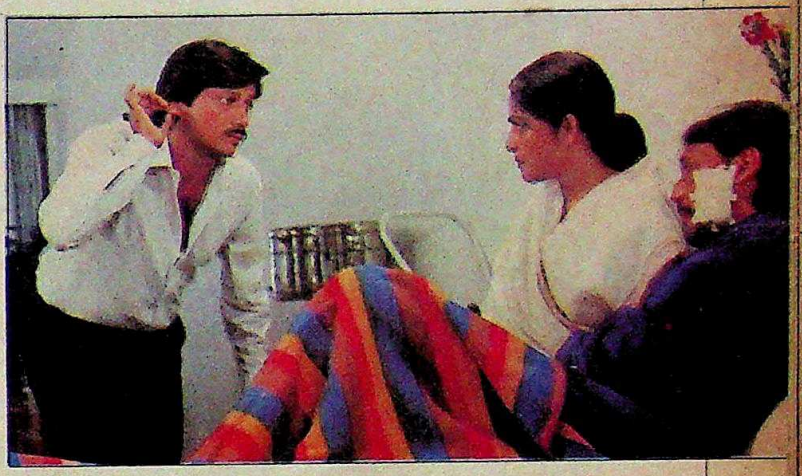

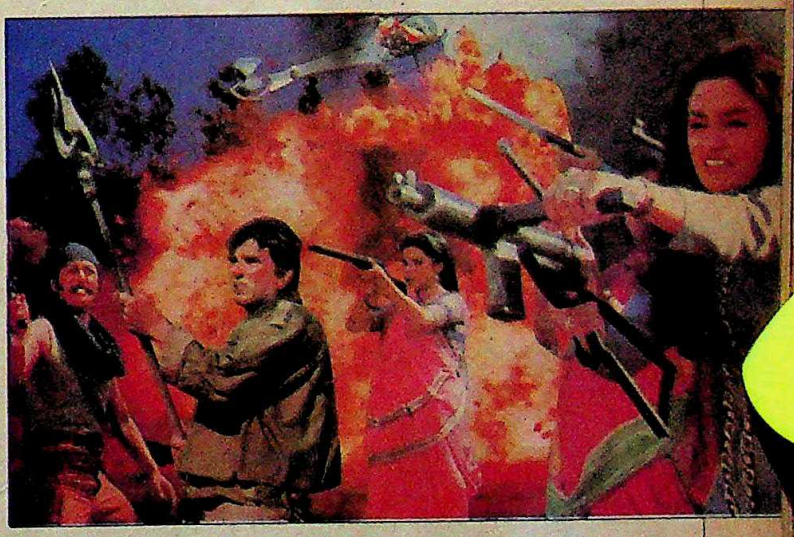

पिटी हुई फिल्मों के दृश्य (ऊपर से) *फलक*; *मर्दों वाली बात*; और *अल्लारक्खा*

CC-0. In Public Domain. Gurukul

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भवान सिंह

राज बंब्बर, राज सिप्पी और शत्रुघ्न सिन्हा

बुलबुला ठीक वैसे ही फूट पड़ेगा जैसे तीन साल पहले तेलुगु फिल्मोद्योग में फूटा था.''

एक जमाना था जब हिंदी फिल्मोद्योग धड़ाधड़ रजत जयंती वाली फिल्में बनाता था. उसके पास 'सिल्वर जुबली स्टार' राजेंद्र कुमार भी थे. मौजूदा स्थिति पर उन्हीं का कहना है, ''यह उतार-चढ़ाव का जमाना है. अब तक्नीशियनों और कलाकारों की बन आई है जबकि वितरक और प्रदर्शक धूल चाट रहे हैं.''

आज कोई फिल्म अगर पूरे देश में चार हफ्ते से अधिक तक हाउसफुल चल जाए तो उसे सफल माना जाता है. निर्माता-निर्देशक मनमोहन देसाई के मुताबिक पिछले दो वर्षों में श्रीदेवी की *नगीना*, और *प्रतिघात* को ही रजत जयंती मनाने का यह 'सम्मान' मिला है. यह सही है कि अब पहले के मुकाबले नई फिल्मों के बहुत ज्यादा प्रिंट बनाए जाते हैं लेकिन इससे उनके वितरण का खर्च भी तो बढ़ता है. मसलन अमिताभ को लेकर बनी टीनू आनंद की फिल्म *शहंशाह* के 250 प्रिंट तैयार किए गए थे और हर प्रिंट पर 55,000 रु. लागत आई थी. तीन साल पहले जब वीडियो की इतनी धूम नहीं थी, किसी बड़ी फिल्म के औसतन 60 से 70 प्रिंट तैयार किए जाते थे. लेकिन वक्त की नजाकत को देखते हुए निर्माताओं ने छापामारों जैसे दांवपेंच अपना लिए हैं यानी ज्यादा से ज्यादा सिनेमाघरों में अपनी फिल्मों के प्रिंट पहुंचाओ, फिर जल्दी से पैसा बटोरो और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म के दम तोड़ने से पहले ही रफूचक्कर हो जाओ. हाल ही में रिलीज दो नई फिल्मों—हरमेश मल्होत्रा की 130 प्रिंटों वाली *शेरनी* और महेश भट्ट की 120 प्रिंटों वाली *कब्जा* से यही प्रवृत्ति देखने को मिलती है. पश्चिमी भारत में ही *शहंशाह* के 50 प्रिंट वितरित किए गए थे. बंबई के वितरक को यह फिल्म करीब एक करोड़ रु. में पड़ी थी. पर 12 हफ्ते बाद भी वे इस फिल्म से एक करोड़ से कुछ ही अधिक कमा पाए.

हम बहुत तेज रफ्तार से चल रहे हैं. मुझे अंदेशा है कि किसी दिन हिंदी फिल्मोद्योग का बुलबुला ठीक वैसे फूट जाएगा जैसे तीन साल पहले तेलुगु फिल्मोद्योग में फूटा था''

राज सिप्पी

अरसे से हिंदी सिनेमा की नैया खे रहे अमिताभ की यह ताजा फिल्म देश के कुछ हिस्सों में तो चार हफ्ते भी नहीं चल पाई, हालांकि *आखिरी रास्ता* के पूरे एक साल बाद उनकी कोई फिल्म रिलीज हुई थी. *आखिरी रास्ता* भी बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कामयाब नहीं रही थी. फिर भी अमिताभ इस समय पहले से भी ज्यादा व्यस्त हैं. वे एक साथ 10 फिल्मों में काम कर रहे हैं. हिंदी सिनेमा में आई तेजी या मंदी (आप इसे चाहे जिस नजरिये से देखें) से पहले वे उद्योग में सबसे ज्यादा पेशेवर स्टार माने जाते थे और एक दिन में एक ही फिल्म की शूटिंग के नियम का कड़ाई से पालन करते थे. पर पिछले पखवाड़े वे सुबह जहां रमेश सिप्पी की *अकेला* में एक सख्त पुलिसिए की भूमिका कर रहे थे, वहीं तुरंत बाद केतन देसाई की *तूफान* में भगवे कपड़े पहने देसी फैंटम का रूप धर रहे थे.

फिर भी अमिताभ फिल्मोद्योग के अनेक दूसरे सितारों की तरह खुद को इतनी यातना नहीं दे रहे. लंबे समय की गैर-मौजूदगी के बाद भी बिना छवि खोए फिल्म जगत में लौटने वाले विनोद खन्ना पिछले पूरे पखवाड़े बंबई के कई स्टुडियो की खाक छानते रहे. एक दिन तो वे सुबह 5.30 बजे तक *आखिरी अदालत* की शूटिंग में जुटे रहे.

एंग्री यंगमैन *शहंशाह* बनकर आए तो कई जगह चार हफ्ते भी दर्शकों को बांधे नहीं रख सके. यहां तक कि उनकी अपनी बंबई में भी कमाई निराशाजनक ही रही

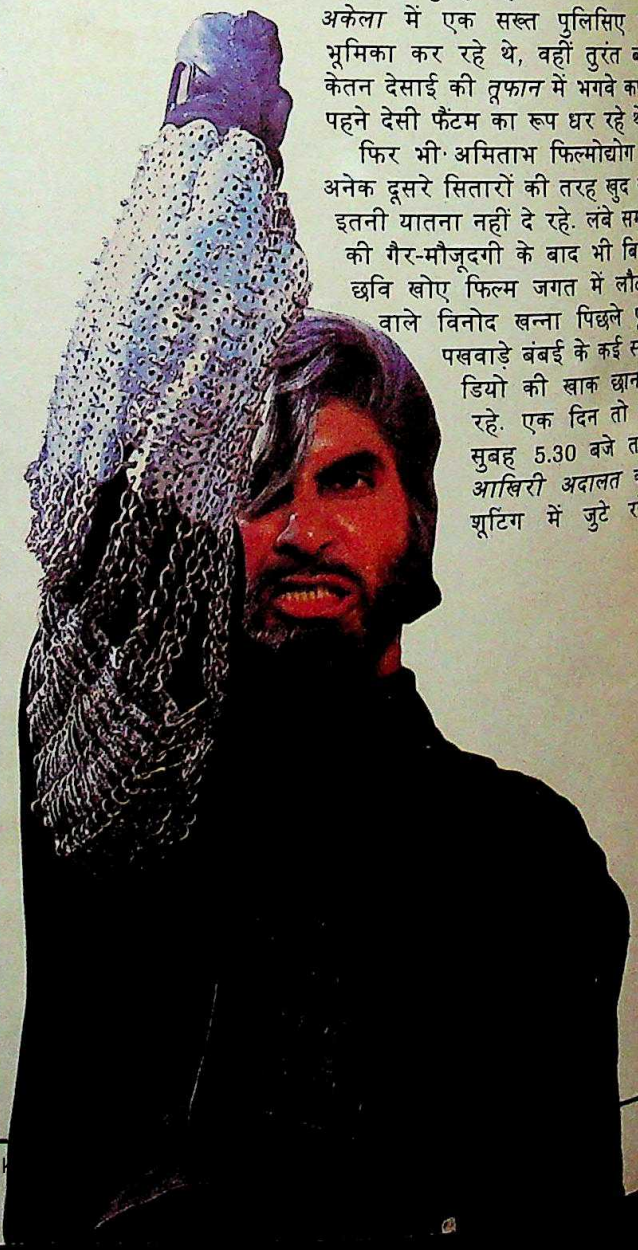

CC-0. In Public Domain. Guruk

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

...विनोद खन्ना कहते हैं, "अगर कोई एक साथ ...या तीन फिल्में कर सके तो बिलकुल सही ...रहता है. पर मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा ...जो ऐसा करते हैं उनमें प्रतिभा नहीं होती."

लेकिन कुछ दूसरे सितारे काम के ...आधार शेड्यूल का विरोध करने लगे हैं. ...अरसे बाद फिर से स्टार की हैसियत में ...डिंपल को अब लगता है कि "अभिनय ...मजा नहीं रहा." वे कुमार शाहनी की ...कारनीना और सई परांजपे की अगली ...के लिए समय न निकाल पाने की ...से परेशान हैं वे मानती हैं, "मेरे ...बहुत से सितारों को अपनी फिल्में कम ...देनी चाहिएं. लेकिन यह झूठ है कि ...ही पैसा कमा रहे हैं. अगर निर्माताओं ...फायदा नहीं होता तो वे सितारों के ...क्यों भागते फिर रहे हैं."

फिल्मोद्योग में उतार-चढ़ाव का जमाना आ गया है. तक्नीशियनों और कलाकारों की बन आई है. फिल्मों के वितरक और प्रदर्शक धूल चाट रहे हैं"

राजेंद्र कुमार

नामस भोजानी

थोड़े से कमाऊ सितारों को अनुबंधित करने की इस होड़ में ...सितारों के भाव एक साल से भी कम अरसे में दुगने हो गए हैं. बताया ...जाता है डिंपल अब एक फिल्म के करीब 15 लाख रु. लेती हैं. ...अभिनेत्रियों में श्रीदेवी का नंबर सबसे ऊपर है. 20 लाख की कीमत ...कर लेने वाली वे पहली हीरोइन हैं. मिथुन चक्रवर्ती और विनोद ...अब अपनी फिल्मों के लिए 40 लाख रु. मांग सकते हैं. ...अमिताभ की तरह मिथुन भी भुगतान के तौर पर अब किसी इलाके में ...फिल्म वितरण के अधिकार मांगते हैं. फिर भी चार निर्माताओं ने ...अपनी फिल्मों में अमिताभ और मिथुन को अनुबंधित किया है.

हालांकि मिथुन की ताजा फिल्म *प्यार का मंदिर* अच्छी चल रही ...फिर भी उन्हें चिंता है कि इस साल उनकी 18 फिल्में रिलीज ...होंगी. पर उन्होंने मई 1989 से फिल्में कम कर देने की योजना बनाई ...तब वे छह महीने में चार से ज्यादा फिल्में नहीं करेंगे. वे खुशी से ...कहते हैं, "यहां कोई संकट-वंकट नहीं है. उद्योग फल-फूल रहा है, हर ...रोज दो-तीन मुहूर्त होते हैं." मनमोहन देसाई की *गंगा-जमुना-सरस्वती* में भूमिका के बाद वे राजकुमार कोहली की *बीस साल बाद* ...के लिए मेकअप कर रहे हैं कि ड्रेसिंग रूम में झांकते हुए डिंपल लय में ...बोल उठती हैं, "समय ही पैसा है, समय ही पैसा है."

20 साल से उद्योग में जमे पुराने कलाकारों की भी अचानक ही मांग बढ़ गई है. धर्मेंद्र, जीतेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा की झोली में दर्जनों फिल्में हैं. 29 फिल्मों में काम कर रहे शत्रुघ्न कहते हैं, "आज जिसे देखो निर्माता बना फिरता है. फिल्मोद्योग में पैसा आने से लोग इतने उतावले हो गए कि मूल अर्थशास्त्र ही भूल गए हैं." पर मौजूदा दौर को एक 'रहस्य काल' मानने वाले शत्रुघ्न का अनुमान है, "अगर फिल्म निर्माण में हो रही बढ़ोतरी मुंह के बल आन गिरी तब तो फिर भगवान ही मालिक है. पर अगर फिल्में बनाना लाभप्रद होता है तो फिर तरक्की को कोई रोक नहीं सकेगा."

फिल्म निर्माण के इस झोंके से जहां फिल्मी सितारे फूले नहीं समा रहे, वहीं उद्योग के कुछ दूसरे लोग भविष्य की चिंता में घुल रहे हैं. निर्देशक महेश भट्ट चेतावनी देते हुए कहते हैं, "हमें वक्त की पुकार सुननी होगी. हम संकट से गुजर रहे हैं. अब तो आशा-वादिता भी पागलपन लगने लगेगी."

भारतीय चलचित्र निर्माता संघ (इंपा) के अध्यक्ष रामलाल नाहटा के अनुसार आज जो हो रहा है उससे तीन साल पहले फिल्मोद्योग पर आए संकट से भी बड़ा संकट आ सकता है. उद्योग का मौजूदा संकट इतना बिखरा और बंटा हुआ है कि फिल्मकार तब तक इसका अंदाज नहीं लगा सकते जब तक कि नई फिल्में सिनेमाघरों में

आज जिसे देखो फिल्म निर्माता बना फिर रहा है. फिल्मोद्योग में भारी पैसा आने से लोग इतने उतावले हो गए कि मूल अर्थशास्त्र ही भूल गए हैं"

शत्रुघ्न सिन्हा

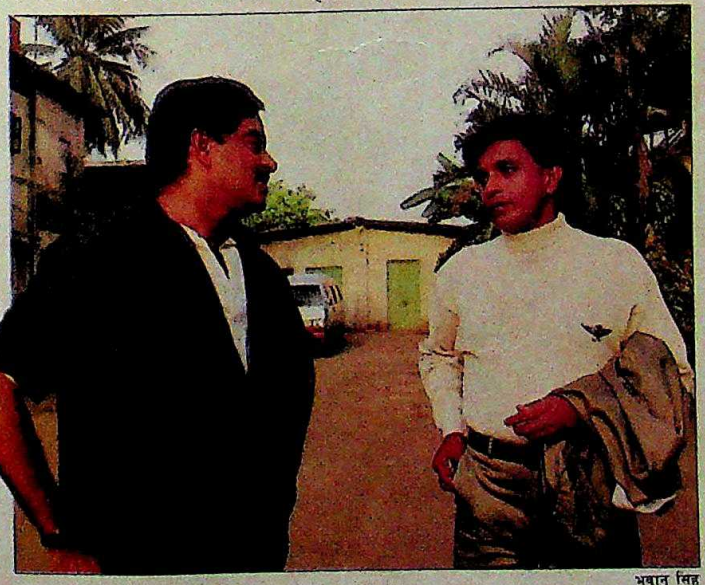

भवान सिंह

फिल्मोद्योग में कोई संकट-वंकट नहीं है. फिल्म नगरी फल-फूल रही है. हर रोज यहां दो-तीन फिल्मों के मुहूर्त हो रहे हैं. हर स्टार आज व्यस्त है"

मिथुन चक्रवर्ती

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नहीं पहुंच जातीं. अभी बन रही नई फिल्मों के प्रदर्शन का सिलसिला पूरे 1988 में चलने वाला है. नाहटा चेताते हैं, "जो कुछ होगा उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता. अब बॉक्स ऑफिस पर कोई फिल्म ज्यादा देर नहीं चल सकती. मुझे लगता है इस साल के आखिर में हमें नाकामी का सामना करना ही पड़ेगा."

वितरकों और प्रदर्शकों को पतन का दौर शुरू होने में कम ही संदेह रह गया है. राजश्री पिक्चर्स ने *प्रतिघात* के अखिल भारतीय वितरण के अधिकार लेकर खूब कमाई की थी पर उसके बाद उसने एक भी फिल्म वितरित नहीं की है. ताराचंद बड़जात्या कहते हैं, "हालत खस्ता है. फिल्मोद्योग में मैंने पहले कभी इतना गोलमाल नहीं देखा." उनके बेटे कमल बड़जात्या कहते हैं, "फिल्मों के निर्माण और वितरण खर्च के हिसाब से अब बॉक्स ऑफिस की कमाई कुछ नहीं रह गई है."

"सिनेमा एक उम्रदराज वेश्या की तरह है. अब टीवी, वीडियो नाम की नई डायनें आ गई हैं"
महेश भट्ट

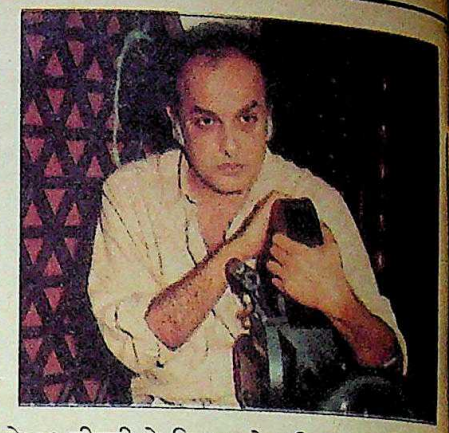

तिरुपति फिल्म्स के रमेश लुढ़ानी बताते हैं कि उनकी कंपनी ने पिछले 18 महीनों से एक भी फिल्म नहीं खरीदी. 1986 में तिरुपति फिल्म्स को दो बड़ी फिल्मों में भारी नुकसान उठाना पड़ा. बंबई क्षेत्र में *सल्तनत* के वितरण पर इसने 65 लाख रु. खर्च किए जबकि वापस आए सिर्फ 30 लाख रु. इसी तरह *सिंहासन* के वितरण पर 60 लाख रु. खर्च हुए लेकिन उससे भी 30 लाख रु. ही मिले. लुढ़ानी को लगता है कि जब तक राज्य सरकारें टैक्स कम नहीं करतीं (टिकट खिड़की से मिली रकम का 50 फीसदी तो मनोरंजन कर के रूप में ही चला जाता है) और निर्माता दर्शकों को परिवार समेत फिर हॉल में खींच लाने लायक अच्छी फिल्में नहीं बनाते, फिल्मोद्योग संकट से उबर नहीं सकता.

लेकिन इन दोनों में से कोई भी बात हो पाने की संभावना दूर-दूर तक नजर नहीं आती. दरअसल जिस तरह परिवार के साथ फिल्म देखने वाले लोगों का रिश्ता खस्ताहाल सिनेमाघरों से कटता जा रहा है उससे अनेक हॉल बंद होने की स्थिति में पहुंच गए हैं. यूनेस्को ने प्रति 1000 जनसंख्या पर सिनेमाघरों की 33 सीटें होने की सिफारिश की थी. लेकिन भारत में इसका अंशमात्र भी नहीं है. बंगलूर और अहमदाबाद जैसे नगरों के कई सिनेमाघर बंद हो चुके हैं. चार दक्षिणी राज्यों के बाद सबसे ज्यादा सिनेमाघरों वाले राज्य महाराष्ट्र में हॉल बंद करने पर कानूनी रोक लगी हुई है. सिनेमाघर मालिक संघ के अध्यक्ष यू.एन थडाणी के अनुसार, "अगर कानून बदल दिया जाए तो रातोरात महाराष्ट्र के 80 फीसदी सिनेमाघर बंद हो जाएंगे. टैक्स बढ़ते जाने, दर्शकों के न आने और जायदाद की कीमत आसमान छूते जाने से अब सिनेमाघर बंद करके उनकी जगह व्यावसायिक कांप्लेक्स बनाना ज्यादा फायदेमंद सौदा हो गया."

पहले निर्माता फिल्म की शूटिंग के दौरान ही वितरण के अधिकार बेचकर कुछ पैसा जुटा लेते थे. बॉक्स ऑफिस की हालत खराब होने से अब वितरक बहुत चौकन्ने हो गए हैं. भारतीय चलचित्र वितरक संघ के अध्यक्ष एन.एन. सिप्पी का अंदाज है कि जो 400 फिल्में बनने के दौर में हैं उनमें से मुश्किल से 10 फीसदी के वितरण के अधिकार ही पहले से बिक पाए होंगे. तैयार हुई 180 फिल्मों में से सिर्फ 20 को ही सभी क्षेत्रों में वितरण के लिए खरीदार मिल पाए हैं. बंबई और मद्रास की 11 बड़ी प्रोसेसिंग लेबोरेटरियों में कई फिल्में पड़ी हैं क्योंकि इनके निर्माताओं को वितरक नहीं मिल रहे हैं. फिल्म सेंटर लेबोरेटरी के मालिक रमेश पटेल कहते हैं, "पिछले साल भर में हमारे यहां 25 ऐसी फिल्मों का अंबार लग गया जिन्हें लेने कोई नहीं आया." एन.एन. सिप्पी कहते हैं, "भारी बदलाव आ चुका है. अब वह जमाना गया जब लोग आंख मूंदकर फिल्में खरीद लेते थे."

चूंकि निर्माताओं को अपनी फिल्मों के ग्राहक ढूंढ़ने में मुश्किल हो रही है इसलिए वितरकों से उनके परंपरागत रिश्ते भी बदलते जा रहे हैं. बालकृष्ण श्रॉफ कहते हैं, "निर्माता फिल्म बेचने में असमर्थ हो जाते हैं तो वे या तो वितरकों के भागीदार बनकर टिकट खिड़की का जोखिम उठाते हैं या फिर अपनी फिल्मों की कीमत घटा देते हैं. आज 50 फीसदी फिल्में अनुमानित कीमत से कम पर जा रही हैं."

मध्य प्रदेश, राजस्थान और विदर्भ के वितरकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सेंट्रल सर्किट सिने एसोसिएशन (सीसीसीए) ने यह एलान करके तहलका मचा दिया है कि वे 12 या उससे ज्यादा फिल्मों में काम कर रहे सितारों की फिल्मों को हाथ भी नहीं लगाएंगे. एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष सिंह जैन ने, जो असरदार फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के भी अध्यक्ष हैं, उन सितारों की बाकायदा सूची जारी की जिनकी फिल्में वितरकों के बहिष्कार की जद में आती हैं. इस सूची में हिंदी सिनेमा जगत के बड़े-बड़े नाम हैं. जैसे—धर्मेंद्र (30 फिल्में इनके पास हैं), शशि कपूर (25), मिथुन चक्रवर्ती (31), राज बब्बर (31), शत्रुघ्न सिन्हा (29), विनोद खन्ना (23), जीतेंद्र (16), ऋषि कपूर (15), अनिल कपूर (18), गोविंदा (33) और

"अगर कोई अभिनेता एक साथ दो या तीन फिल्में ही करे तो ठीक रहेगा. लेकिन मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा"
विनोद खन्ना

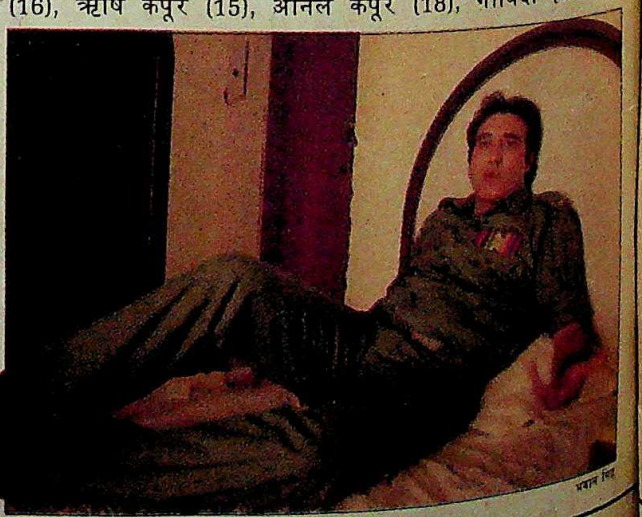

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

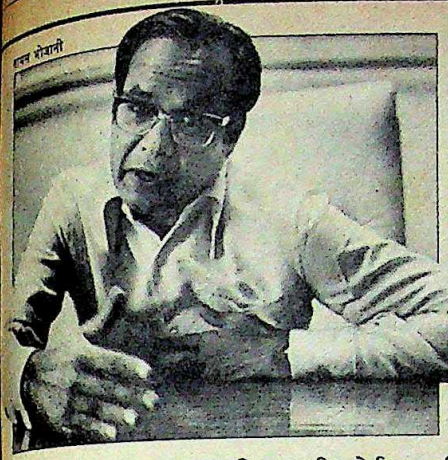

"निर्माण और वितरण खर्च के अनुपात में बॉक्स आफिस की कमाई कुछ न रही"

कमल बड़जात्या
निर्माता और वितरक

संजय दत्त (23). यहां तक कि अपनी कोई एक फिल्म भी हिट होने की उम्मीद लगाए बैठे चंकी पांडे भी इस सूची में हैं. उनके पास 22 फिल्में हैं. बड़े सितारों में सिर्फ अमिताभ बच्चन और जैकी श्रॉफ ऐसे हैं जिनके पास दस-दस फिल्में हैं.

फिल्में हथियाने के मामले में अभिनेत्रियां भी पीछे नहीं हैं. डिंपल (29 फिल्में इनके पास हैं), मंदाकिनी (29), नीलम (15), क्रिमी काटकर (37), अनीता राज (26), अमृता सिंह (12), फरहा (15), जयप्रदा (21), मीनाक्षी शेषाद्रि (23), माधुरी दीक्षित (16), सोनम (26), और श्रीदेवी (14). हेमा मालिनी (11) और रेखा (10) के पास कम फिल्में हैं.

जैन की शिकायत है, "संकट के लिए खराब फिल्में जिम्मेदार हैं. और फिल्मों का स्तर गिराने का दोष एक साथ 20 से 30 फिल्मों में काम करने वाले सितारों पर जाता है. किसी भी कलाकार को एक फिल्म के लिए कम-से-कम 40 दिन तो देने ही पड़ते हैं. यदि वह ईमानदारी से काम करता है तो एक साथ आठ या नौ से ज्यादा फिल्में कैसे कर सकता है?"

हिंदी फिल्मोद्योग के संकट का दोष अभिनेता-अभिनेत्रियों पर मढ़ने पर रेखा की त्यौरियां चढ़ जाती हैं. वे कहती हैं, "इससे तो काम का स्तर ही सुधरा है क्योंकि निर्देशक को पता होता है कि कलाकार के पास कम समय है, इसलिए वे अपने दृश्यों की बेहतर योजना तैयार करते हैं. अभिनेत्रियों के काम करने का दौर तो पांच से 10 वर्ष का ही होता है. ऐसे में अगर वे ज्यादा से ज्यादा फिल्में लेती हैं तो उनमें गलत क्या है?" पिछले पखवाड़े श्रीनगर में दो फिल्मों की शूटिंग कर रहे जीतेंद्र ने फिल्मी पत्रिका 'फिल्मफेयर' से कहा, "अंधाधुंध फिल्में साइन करने और कई फिल्में लिए बैठे सितारों के पीछे भागते जाने से लागत खर्च आसमान पर पहुंच रहा है. इससे फिल्मोद्योग संकट में पड़ेगा और कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर निश्चित ही पिट जाएंगी."

मिस्टर इंडिया की कामयाबी के बाद उत्साह से छलकने वाले अनिल कपूर ने भी पिछले दो महीनों में 10 फिल्में छोड़ दी हैं. अनिल को लगता है कि सेट पर देर से पहुंचने से उन्हें ग्लानि होती है. वे कहते हैं, "मेरे 90 फीसदी दोस्तों को लगता है कि फिल्में छोड़कर मैं बेवकूफी कर रहा हूं. लेकिन मुझे लगता है कि अगर सेट पर बढ़िया काम करना है तो उस फिल्म को पूरा समय देना ही पड़ेगा."

लेकिन राज बब्बर को लगता है कि सितारों के सिर पर बेवजह दोष मढ़ा जा रहा है. फिल्मों के पिटने की असली वजह है खराब पटकथाएं. लेकिन भविष्य को लेकर वे भी चिंतित हैं. उनका कहना है, "हम बरबादी की ओर बढ़ रहे हैं. 1989 की शुरुआत में फिल्में तो कई तैयार हो जाएंगी लेकिन खरीदने वाला कोई न होगा."

मध्य भारत के वितरकों द्वारा फिल्मी सितारों के बहिष्कार से हिंदी फिल्मोद्योग के गंभीर संकट की ओर ध्यान खींचने से ज्यादा शायद ही कुछ होगा. जैसा कि अखिल भारतीय फिल्म निर्माता परिषद के अध्यक्ष विजय आनंद कहते हैं कि एक साथ 12 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले सितारों की फिल्मों का बहिष्कार किया जाता है तो फिर वितरकों को खरीदने के लिए कौन-सी फिल्में बचेंगी? आनंद कहते हैं कि निर्माताओं को संकट से परेशान होने की जरूरत नहीं है. समस्या वितरकों की है और इस संकट का कारण है सिनेमाघरों की कमी तथा वीडियो की बढ़ती लोकप्रियता.

लेकिन पिछले पांच वर्षों में वीडियो ने बड़े शहरों से लेकर दूर-दराज के गांवों तक के सिनेमा बाजार में पांव पसार लिए हैं और वह सिनेमा को किनारे करता जा रहा है. एक अनुमान के अनुसार देश भर में 15 लाख वीडियो कैसेट रिकार्डर, एक लाख वीडियो लाइब्रेरियां, एक लाख वीडियो पार्लर तथा थिएटर हैं. इसके अलावा हजारों होटलों और निजी तौर पर लगे केबल टीवी कनेक्शनों के कारण हर महीने तीन लाख वीडियो कैसेटों की बिक्री के लिए तैयारशुदा बाजार मिल जाता है. अनुमान है कि अब भारत में वीडियो उद्योग का सालाना कारोबार 1,000 करोड़ रु. का है और देश के 12,732 सिनेमाघरों की कुल आमदनी भी करीब इतनी है.

महेश भट्ट कहते हैं, "सिनेमाघरों की पहचान खत्म हो रही है. अब सिनेमा एक उम्रदराज वेश्या की तरह है जिसका आकर्षण खत्म हो रहा है पर वह आस लगाए बैठी है उसकी जवानी लौट आएगी. पर अब बहुत बुरा समय आ गया है. शहर में वीडियो और टीवी नाम की नई डायनें आ गई हैं." मनमोहन देसाई को लगता है कि उद्योग को बचाए रखने का एक ही उपाय है कि सिनेमाघरों को वीडियो थिएटरों में बदल दिया जाए. वे कहते हैं, "वीडियो, फिल्म के ट्रेलर की तरह हो गया है. यदि लोगों को कोई फिल्म वीडियो पर पसंद आई तो वे उसे सिनेमाघरों में जाकर देखते हैं. पहले स्थिति ठीक इसे उलट थी." विनोद खन्ना का मानना है कि सिनेमा का गौरव वीडियो

भवान सिंह

"यह झूठ है कि सितारे ही पैसे कमा रहे हैं. निर्माताओं को कुछ नहीं मिलता तो वे सितारों के पीछे क्यों भागते हैं?"

डिंपल कपाडिया

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भवान मिश्र

"अभिनेत्रियों के काम करने का दौर तो पांच से दस वर्ष का ही होता है. अगर वे ज्यादा फिल्में करती हैं तो गलत क्या है?"
रेखा

को मिलने की प्रक्रिया अब चल पड़ी है, "जल्दी ही वीडियो किसी महत्वपूर्ण वितरण क्षेत्र जितनी कमाई करने लगेगा." निर्देशक रमेश सिप्पी कहते हैं, "मुझे लगता है कि अगले पांच वर्षों में वीडियो और टीवी कारोबार बहुत बढ़ जाएगा."

फिर भी दो निर्माता-निर्देशकों का अनुभव इस तथ्य की ओर ध्यान खींचता है कि फिल्म नगरी अनिश्चितताओं और जादुई अपवादों से भरी पड़ी है. हरमेश मल्होत्रा बताते हैं कि हाल की दो बेहद हिट फिल्में, उनकी अपनी फिल्म *नगीना* और राजकपूर की *राम तेरी गंगा मैली* वीडियो अधिकार बेचे बगैर ही रिलीज कर दी गई थीं. नतीजतन बाजार में इन दोनों फिल्मों के चोरी से बनाए वीडियो कैसेट बिकने लगे. मल्होत्रा कहते हैं, "मुझे सौ फीसदी यकीन है कि यदि फिल्म अच्छी है तो लोग चोरी के कैसेटों के घटिया स्तर से निराश होकर सिनेमाघरों में जाकर फिल्म देखने को मजबूर होंगे."

अमित खन्ना का कहना है कि वीडियो चोरी का हो-हल्ला फिल्मोद्योग की दूसरी खामियों पर परदा डालने के लिए किया जा रहा है. वे कहते हैं, "भारत में सबसे ज्यादा फिल्में बनती हैं पर सिनेमाघरों में प्रति व्यक्ति के हिसाब से सीटें सबसे कम उपलब्ध हैं." जहां फिल्मों का निर्माण खर्च बढ़ रहा है, वहीं उनकी लागत और बिक्री की दर के बीच का फर्क घट रहा है. रमेश सिप्पी कहते हैं, "यदि मुद्रास्फीति को ध्यान में रखा जाए तो फिल्मों की बिक्री दर पिछले चार साल में कतई नहीं बढ़ी जबकि फिल्मों का निर्माण खर्च तीन या चार गुना बढ़ गया है."

अंधाधुंध फिल्म निर्माण की धुन में एक के बाद दूसरी प्रोडक्शन यूनिट आगे बढ़ती जा रही है लेकिन इस अंधी दौड़ में हिंदी फिल्मों के तेजी से गिरते स्तर को एकदम भुला ही दिया गया है. हृषिकेश मुकर्जी की 14 फिल्मों में काम कर चुके अभिनेता देवेन वर्मा कहते हैं, "पूरी तरह से हास्य-व्यंग्य प्रधान फिल्मों का वक्त अब नहीं रहा. अब *जिंदा जला दूंगा* जैसी फिल्मों का जमाना आ गया है. हम हिंसा की संस्कृति को जन्म दे रहे हैं जिसमें बदला लेना ही सबसे बड़ी भावना बन गई है."

पर विदेश से आने वाली बिना सेंसर की हुई बहुत ही अश्लील और भयानक फिल्में हजारों वीडियो पार्लरों में दिखाए जाने से हिंदी फिल्मों के निर्माताओं ने पाया कि लोगों की सेंसर की हुई देसी हिंसा में अब कोई रुचि नहीं रही है. मनमोहन देसाई की शिकायत है, "हिंदी फिल्में नहीं बल्कि सेंसर न की गई वीडियो फिल्में ही दर्शकों की रुचि बदल रही हैं और सरकार की सेंसरशिप की नीति का मखौल उड़ा रही हैं."

यहां तक कि देवानंद जैसे करिश्माई सितारे भी, जिनकी पुरानी प्रेम फिल्में दर्शकों को हमेशा भरपूर आनंद देती हैं, अब हिंसा की नई संस्कृति अपनाने पर मजबूर हो रहे हैं. देवानंद की ताजा फिल्म *सच्चे का बोलबाला* सितंबर में रिलीज होने वाली है. वे अफसोस से स्वीकार करते हैं, "मुझे अपनी फिल्म में मारधाड़ के दृश्य घुसेड़ने पड़े, नहीं तो लोग कहते मैंने 'शाकाहारी' फिल्म बना दी है."

पर हिंदी सिनेमा चाहे जितने मारधाड़ वाले दृश्य दिखाने लगे, दर्शकों का चित्त अस्थिर ही दिखाई देता है. हालांकि बंबई और मद्रास के फिल्म निर्माता महंगे से महंगे सेटों पर अपनी फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं पर उनमें दर्शकों की दिलचस्पी कम से कमतर होती जा रही है. इसका परिणाम यह है कि सिर्फ सितारों के चेहरों पर ही थकान भरी हंसी दिखाई देती है. देसाई कहते हैं, "आजकल हिंदी फिल्मोद्योग मानो पूरी तरह से सितारों के फायदे के लिए ही चल रहा है."

बड़े सितारों के आभामंडल के मोहपाश में बंधे और नोटों के पुलिंदे लिये फाइनांसरों की अंतहीन कतार देखकर फिल्मोद्योग के कई लोगों को लगता है कि इस मायानगरी की चमक-दमक कभी खत्म नहीं होगी. मिथुन का कहना है, "मुझे तो कोई संकट दिखाई नहीं देता. यह (फिल्मोद्योग) तो एक कैसिनो (जुआघर) है जहां लोग अपनी जेबों में 2 से 5 करोड़ रु. तक लेकर चले आते हैं. हर कोई तो जीत नहीं पाता पर हर कोई हारता भी नहीं है."

पर अमित खन्ना इससे सहमत नहीं हैं, "पूरे उद्योग में शेखी बघारने की मनोवृत्ति दिखाई देती है. हम सभी रूसी रुलेट (एक तरह का खेल) खेल रहे हैं. इसमें जो रण छोड़ जाता है, वही जीतता है." फिर भी जब तक सितारों से सम्मोहित धनकुबेर थैलियों का मुंह फिल्मोद्योग की ओर खोलते रहेंगे और सितारे चमकते रहेंगे, गुलगपाड़ों से भरपूर ढेर सारे फिल्मी स्टुडियो से शिकायत का एक भी स्वर सुनाई नहीं देगा. यानी फिल्मोद्योग को कभी शोलों को झेलना पड़ेगा तो कभी शबनमी सुकून हासिल होती रहेगी.

—एम. रहमान

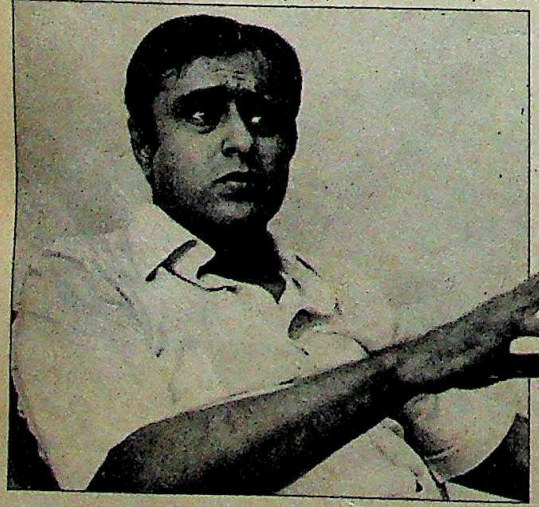

"फिल्मोद्योग में शेखी बघारने की मनोवृत्ति दिखती है. हम रूसी 'रुलेट' खेल रहे हैं. जो रण छोड़ता है, वही जीतता है"
अमित खन्ना
निर्माता-लेखक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पुरानी यादें, नए फसाने

भारत सरीखा गरीब देश इतने बड़े फिल्मोद्योग का बोझ नहीं उठा सकता. लेकिन हालात कैसे भी रहे, भारतीय दर्शक हिंदी सिनेमा से कभी जुदा नहीं हुआ. बरसात हो या कड़ी धूप, बाढ़ हो या अकाल हिंदी सिनेमा ने उसे अपने सम्मोहन में बांधे रखा.

फिल्मोद्योग अपने सितारों की चमक से जगमगाता रहा है. देश के असली हीरो तो यहीं की पैदाइश हैं. राजकपूर के चलने के ढंग की नकल गलियों के हीरो तुरंत करते रहे हैं और कामिनी कौशल का बुंदे गले का परिधान एकाएक ही पूरे देश में फैशन बन गया था. बच्चे एक दूसरे पर 'अरे ओ सांभा' का जुमला कसते रहे हैं और युवा प्रेमी यह कल्पना करते हुए पुराने गीत दोहराते रहे हैं मानो वे राजकपूर और नरगिस हों या दिलीप कुमार और वैजयंतीमाला. फिल्मी सम्मोहन ने पूरे देश को 75 वर्षों से कब्जे में कर रखा है.

एक सुनसान फुटपाथ. फुटपाथ की वही पुरानी बत्तियां. फटा-पुराना छाता लिये एक अकेला शख्स सब प्रकट होता है तो रिमझिम बारिश होने लगती है. इस शख्स के बेतरतीब कदमों की ताल पूरे भारत के दिल की धड़कन बन जाती है. लाखों लोग नरगिस की दबी-ढकी कामुक अदाओं और राजकपूर की आंखों में झलकती मासूमियत को अब भी याद करते हैं. यहां तक कि स्कूली लड़के भी उनकी मुहब्बत की दास्तान अच्छी तरह जानते हैं.

लगता है उन दिनों जैसे सिर्फ अच्छी फिल्में ही बना करती थीं. सीधी-सादी कहानियों के उस युग में राजकपूर, दिलीप कुमार और देवानंद जैसे रोमांटिक हीरो परदे पर छाए हुए थे

एक वक्त था जब निर्देशक प्रतिभासंपन्न दिग्गज हुआ करते थे. प्रतिभा की वजह से उनका आदर किया जाता था. महबूब खां ऐसे ही एक शख्स थे. भारत की पहली रंगीन फिल्म *आन* की अभिनेत्री रही नादिरा कहती हैं, "जिस रास्ते से महबूब खां गुजरते थे हम उसकी धूल सिर-माथे लगाते थे. वे एक असाधारण शख्सियत थे. मैंने उनसे एक बार पूछा कि अभिनय का मतलब क्या है. उन्होंने कहा: देखो, एक्टिंग तो दरिया है, तुम जितना दूर जाओगी, उतना ही पाओगी."

अब तो ऐसा लगता है कि उस जमाने में ही सिर्फ अच्छी फिल्में बनती थीं. सशक्त किरदारों की मिसाल लें: के. आसिफ की *मुगले आज़म* में सलीम को उद्धत चुनौती देता मधुबाला का जीवंत अभिनय और फिर उनका गाना 'प्यार किया तो डरना क्या' जिसने तमाम दर्शकों को भावनाओं से सराबोर कर दिया. *चलती का नाम गाड़ी* के गाने 'पांच रुपैया बारा आना' में किशोर कुमार को लौटने से 'ना' कहने की उसकी शरारत भरी अदा जैसे भारत के सिने इतिहास की विरासत बन गई है. यही विरासत *साहब, बीवी और गुलाम* में मीना कुमारी के अविस्मरणीय अभिनय में और वहीदा रहमान की *कागज के फूल* और *खामोशी* में भी झलकती है. वहीदा कहती हैं, "उस वक्त सीधी-सादी कहानियों पर फिल्में बनाना मुमकिन हुआ करता था. हर सुंदर, कोमल और नाजुक रचना के लिए

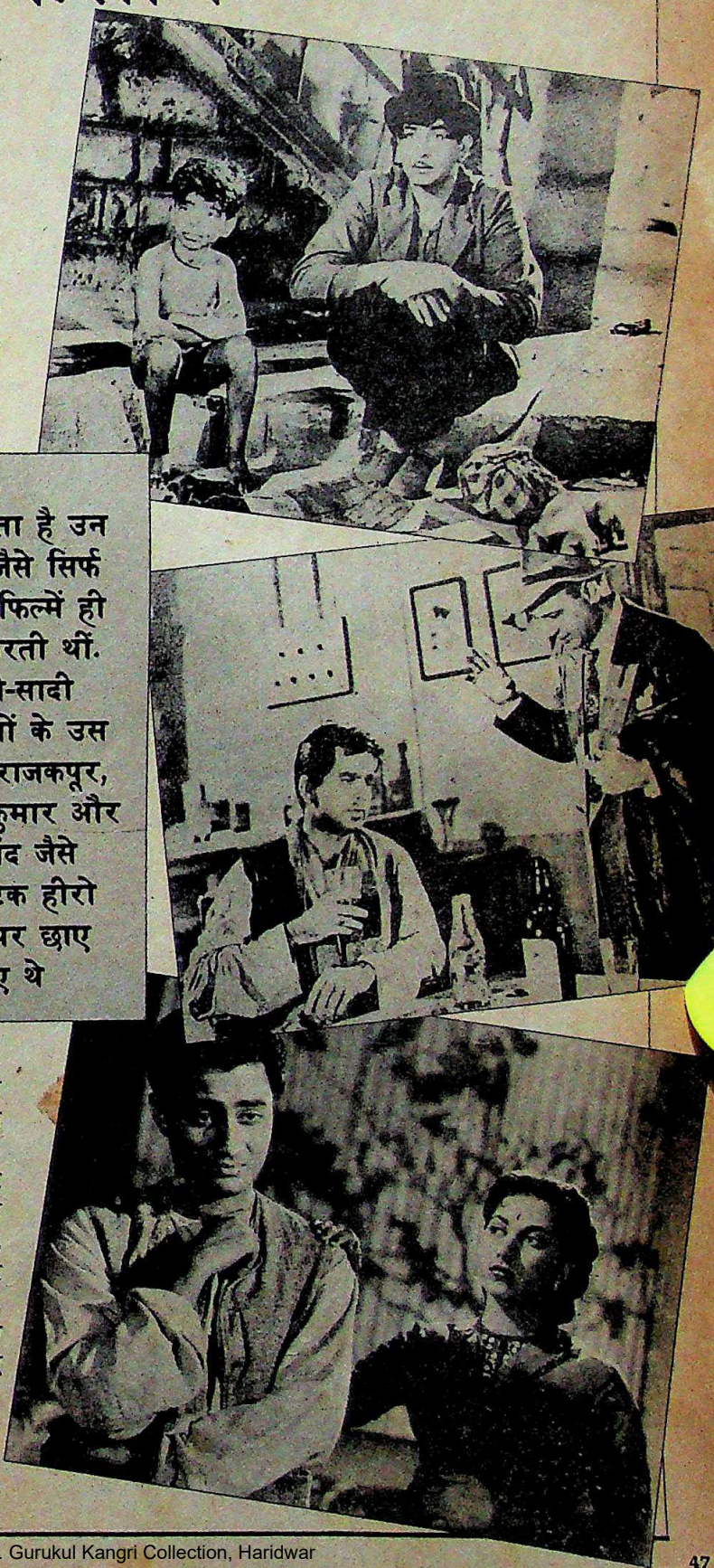

(ऊपर से) *श्री 420* में राजकपूर; *देवदास* में दिलीप कुमार (बाएं) और मोतीलाल; और *सनम* में सुरैया के साथ देवानंद: स्वर्णिम युग

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

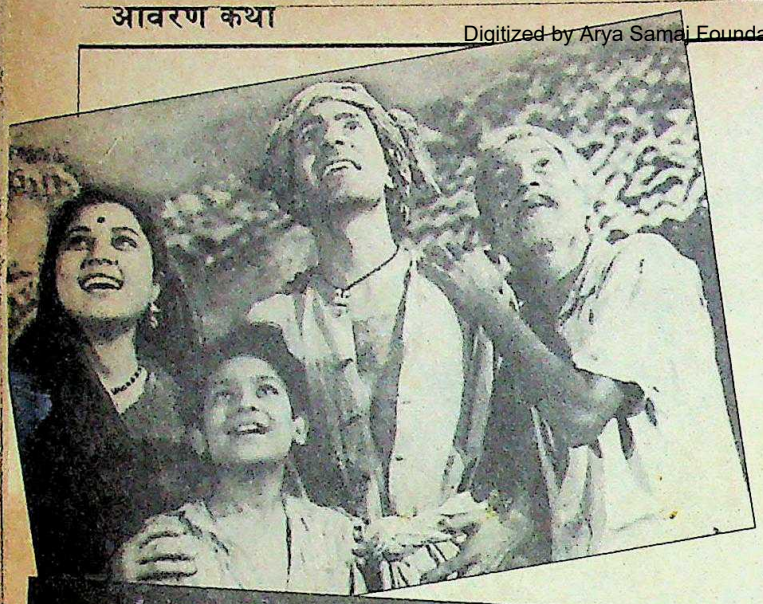

उस जमाने में फिल्मों की लोकप्रियता की वजह थी उनकी कहानियां: प्रेमी हृदयों का मिलन, बिछुड़े परिवारों का पुनर्मिलन और विलन को उसके पाप कर्मों की यथोचित सजा

वक्त की बेहद जरूरत होती है. और भागमभाग के इस युग में हमारे पास यह वक्त नहीं रहा गया है."

ये फिल्में इसलिए लोकप्रिय हुईं क्योंकि इनकी कहानियां एकदम सीधी-सादी थीं. लोग उनमें अपना अक्स देखते थे. भलाई की बुराई पर जीत, बिछुड़े परिवार का पुनर्मिलन और अपराधी को उसके पापों की सजा भुगतनी पड़ती थी. मुहब्बत ऐसी फिल्मों की कहानियों का अहम हिस्सा होती थी. '60 के दशक तक यह चलन साफ दिखता था. तब फिल्म जगत में एक नए प्रेमी का उदय हुआ था—गुरु शर्ट पहने और कंधों पर पतली शॉल डाले राजेश खन्ना का.

प्रेमनाथ कहते हैं, "आज हिंसा हरेक फिल्म की जरूरत बन गई है." शायद यह हमारे दौर की ही झलक है. हल्के-फुल्के रोमांस की जगह एंग्री यंग मैन कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन के धूम-धड़ाके ने ले ली. यह एंग्री यंग मैन एकबारगी ही दर्जन भर लोगों का कीमा बनाते हुए रेखा को अपनी बांहों में भरकर निकल लेता था.

3 मई 1913 को दादा साहब फाल्के की पहली भारतीय फीचर फिल्म *राजा हरिश्चंद्र* आने के 75 साल बाद आज अंदाज भी नहीं लगाया जा सकता कि उस वक्त की दुनिया कितनी आसान और सीधी-सादी थी. तब का जमाना पौराणिक कथाओं, स्टंट फिल्मों, देविका रानी के भेदक कटाक्षों, बिजली-सी कड़कती, लहराती नाडिया और जयराज के परिपूर्ण अभिनय का था.

इसके अलावा एक और बदलाव हुआ—समाज के कायदे-कानूनों में '30 के दशक के पहले तक सिर्फ पारसी, एंग्लो इंडियन महिलाएं और 'गायिकाएं' ही फिल्मों में अभिनय करती थीं. संभ्रांत लड़कियां यह काम हरगिज नहीं करती थीं. प्राण बताते हैं, "उन दिनों अच्छे परिवारों के लोग फिल्मों में नहीं आते थे."

जब 1931 में *आलम आरा* से फिल्मों को जुबान मिली तो जाल इंजीनियर सरीखे अभिनेताओं ने पाया कि उनकी कर्कश आवाज उनके प्रभावी व्यक्तित्व के अनुकूल नहीं बैठती. और इसी वजह से वे फिल्मों से बाहर हो गए. अपनी जेब में 12 रु. और बड़ी उम्मीदें लेकर बंबई आए जयराज पुराने दिनों की याद करते हैं, "बोलती फिल्में अपने साथ खौफ लेकर आईं. जो लोग इसमें माहिर नहीं थे उन्हें ये नागवार गुजरती थीं. वे इन्हें अस्थिरता की जनक और फिजूल मानते थे." लेकिन दो कुलीन मराठी महिलाओं दुर्गा खोटे और शोभना समर्थ ने तो इन फिल्मों में अभिनय करके सनसनी फैला दी.

फिल्मी कथाओं का क्रम रहा: ऐतिहासिक, सामाजिक, रोमांटिक और स्टंट फिल्में. सामाजिक जागरूकता, मसलन सांप्रदायिक सद्भाव और कैदियों का पुनर्वास वी.शांताराम की फिल्मों की विशेषता थी. दीना पाठक कहती हैं, "*सुजाता* (विमल राय की फिल्म) देखने के बाद कोई भी शख्स किसी हरिजन के साथ दुर्व्यवहार करने की सोच भी नहीं सकता."

पिछले 75 साल में फिल्मों की विविधता में खासी कमी आई है. समर्थ कहती हैं "तब कई तरह की फिल्में हुआ करती थीं. जिन्हें आप

(ऊपर से) विमल राय की *दो बीघा जमीन* का दृश्य; *साहब, बीवी और गुलाम* में मीना कुमारी के साथ गुरुदत्त; *मुगले आजम* का दृश्य; (इनसेट) मधुबाला: मर्मस्पर्शी अभिनय

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आजकल कला फिल्में कहते हैं, हमारे जमाने में वे सामान्य फिल्में हुआ करती थीं. और आजकल की सामान्य फिल्मों को हम लोग स्टंट फिल्म कहा करते थे." राजेंद्र कुमार कहते हैं, "और आज सिर्फ ऐसी ही फिल्में बन रही हैं." परिणामस्वरूप आज हिंदी फिल्मों के कथानक का स्तर गिर गया है.

पुराने जमाने में कथानक शानदार इसलिए होते थे क्योंकि उस समय महबूब खां, के. आसिफ, कमाल अमरोही और विमल राय जैसे निर्देशकों का बोलबाला था. *बिराज बहू* की अभिनेत्री कामिनी कौशल विमल राय के बारे में बताती हैं, "उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैंने यह उपन्यास पढ़ा है? मैंने जब बताया कि मैं इसे 20 बार पढ़ चुकी हूं तो उनका आग्रह था कि मैं इसे 20 बार और पढ़ूं ताकि मैं अपने चरित्र में पूरी तरह डूब जाऊं." इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन (इप्टा) और उसके ख्वाजा अहमद अब्बास तथा चेतन आनंद जैसे निर्देशकों और कैफ़ी आज़मी व कृश्न चंदर जैसे प्रगतिवादी लेखकों ने कई लोगों को प्रभावित किया. ऐसी फिल्में उस समय प्रचलित स्टुडियो सिस्टम की देन थीं. कलकत्ता को अपने न्यू थिएटर पर नाज था तो बंबई को बांबे टाकीज़ पर.

पर एक बार स्टुडियो सिस्टम टूटा तो पूरे उद्योग का केंद्र सितारों पर आ टिका. पुराने सितारों को याद करते हुए समर्थ कहती हैं, "तब पृथ्वीराज हुआ करते थे जिनकी शख्सियत का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता था. चंद्रमोहन थे जिनकी केवल शक्लों पर हीं पूरी फिल्म बनाई जा सकती थी. और मोतीलाल थे. कितना सौम्य व्यक्तित्व था उनका!" ज्योंही यह स्पष्ट हुआ कि उद्योग पर सितारों का ही वर्चस्व हो चुका है, एक नई परंपरा शुरू हो गई और अभिनेताओं पर खास 'टाइप' होने के ठप्पे लगने लगे. आजादी के बाद लाहौर से बंबई आए और एक साल तक फुटपाथ पर धक्के खाने के बाद फिल्मी दुनिया में आए ओम प्रकाश कहते हैं, "मैंने दूसरी तरह की भूमिकाएं भी लेने की कोशिश की पर कभी भी ऐसा मौका नहीं दिया किसी ने." प्राण भी इससे सहमत हैं.

लेकिन जल्दी ही भलेमानस हीरो से लोगों का मन ऊब गया. राजेंद्र कुमार का कहना है, "पहले का हीरो बलिदानी और सहनशील होता था. पर आज का हीरो तो अपना अधिकार छीन कर हासिल करता है." शराफत और मासूमियत का जमाना लदा तो हिंदी सिनेमा का एक नया चेहरा सामने आया. असलियत के नजदीक और आत्मा को कचोटने वाली छोटी फिल्में भी बनने लगीं. 1969 के बाद वाले दौर में *भुवन शोम* की सनक, *चक्र* की दिल दहलाने वाली गरीबी, *अंकुर* की करुणा, पुलिस हवालात में होने वाली मौत की अर्धसत्य मार्का सचाई और *अलबर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है* में असलियत के चित्रण की हवा बह चली.

नसीरुद्दीन कटुता से कहते हैं, "हम खास कुछ हासिल तो नहीं कर पाए लेकिन एक दूसरे को इस अंदाज से बधाइयां देते रहे मानो जो कुछ हम कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है. कितना मिथ्याभिमान फैल गया है इस आंदोलन में!"

भारतीय सिनेमा की शुरुआत राजा हरिश्चंद्र से होने के 75 साल बाद आज अंदाज भी नहीं लगाया जा सकता कि तब की दुनिया कितनी सरल और मासूम थी

(ऊपर से) पहली फीचर फिल्म *राजा हरिश्चंद्र*; पुकार में सोहराब मोदी और जिल्लू; *हंटरवाली* में नाडिया; (इनसेट) शोभना समर्थ: पुरानी मोहक दुनिया

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

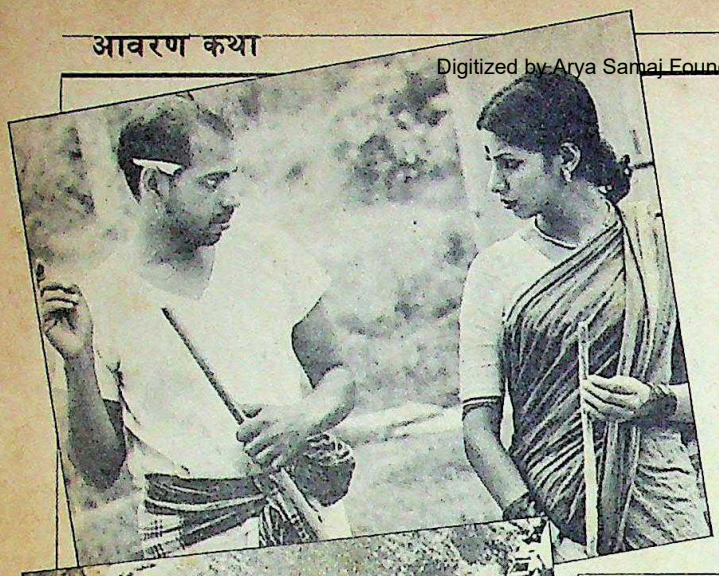

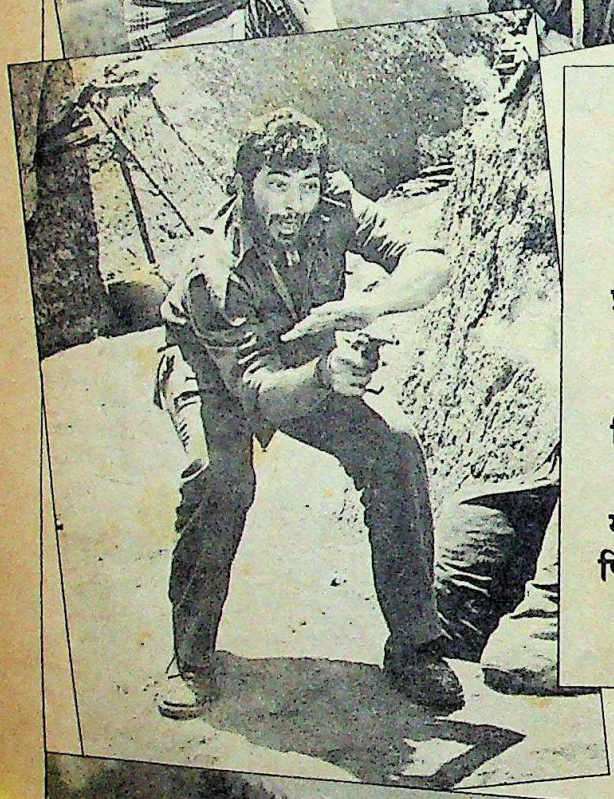

(ऊपर से) *अंकुर* में साधु मेहर और शबाना आजमी; *शोले* में अमजद खां; *राम तेरी गंगा मैली* में मंदाकिनी और राजीव कपूर: नए जमाने की नई लहर

बहरहाल, बॉक्स ऑफिस का ख्याल रखने वाली बड़ी फिल्में बनती ही जा रही हैं. आज जमाना दिखावे का है, तेज तर्रार, बड़बोले युवकों और शर्म-संकोच से कोसों दूर मांसल युवतियों का, जिनके पास ढेरों फिल्में तो हैं लेकिन वे समझ नहीं पा रहे कि आगे क्या करें. यह कहानी है उस यात्रा की जो एक मंदाकिनी से शुरू होकर दूसरी मंदाकिनी तक पहुंची है. पहली मंदाकिनी थी अपने पिता दादा साहब फाल्के की मूक फिल्मों में बाल कलाकार की भूमिका निभाने वाली, तो दूसरी है *राम तेरी गंगा मैली* वाली, भीगी साड़ी में अपने शारीरिक सौंदर्य से कामुकता जगाती.

आज के युग की हिंसा और भागमभाग को प्रतिबिंबित करने वाली फिल्मों ने पुरानी सरल फिल्मों की जगह ले ली है. यह यात्रा है यादगार फिल्मों से न देखने लायक फिल्मों तक की

आज हालत यह है कि सितारों की फिल्में हिट नहीं होतीं और वे एक अंधी दौड़ में जीतोड़ गति से भागते रहते हैं जब तक उनकी नियति उन्हें किसी मुकाम तक न पहुंचा दे. राजेंद्र कुमार चेताते हैं, "पहले यहां निष्ठा थी, अनुशासन था, अपनापन था. आज ये मूल्य नष्ट हो गए हैं." प्राण कहते हैं, "आज के कलाकार इस बात पर खुश होते हैं कि उन्होंने इतनी फिल्में साइन कीं. हम इस बात पर खुश हुआ करते थे कि हमने इतनी फिल्में नामंजूर कर दी." प्रेमनाथ आज के सितारों को 'टैक्सी एक्टर्स' कहते हैं—एक स्टुडियो से दूसरे स्टुडियो तक दौड़ लगाने वाले. देवानंद भी कहते हैं, "हमें कभी इस तरह भाग-दौड़ नहीं करनी पड़ती थी. आज हर व्यक्ति असुरक्षित और असफलता से भयभीत-सा है."

लेकिन इस सबके बावजूद सिनेमा का आकर्षण घटा नहीं है. वातानुकूलित सिनेमा हॉल की बत्तियां गुल होते और घंटी बजते ही निस्तब्धता छा जाती है और सफेद परदे पर एक काल्पनिक किंतु रूपहला संसार जीवंत हो उठता है. एक और नई फिल्म दर्शकों को अपने सम्मोहन में बांध कर सपनों की उस सुहानी दुनिया में ले जाती है, जहां सभी नायक खूबसूरत और जवान हैं, जहां सभी महिलाएं पाक, और हसीन हैं, जहां सभी खलनायक 17 रीलों में आठ गानों, पांच नाचों, चंद बलात्कारों और अंत में किसी सुपरमैन को भी शर्मिंदा कर देने वाली ढिशुम-ढिशुम मार्का लड़ाई के बाद कानून के शिकंजे में आ जाते हैं और अंत भला तो सब भला—सारे बिछुड़े पात्र इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ जोड़े फोटो खिंचवाते हैं और कहानी खत्म. सीधी-सी कहानी है पर 75 वर्षों से लगातार किसी-न-किसी रूप में यह कहानी बार-बार दुहराई जाती रही है. कोई ऊबता नहीं, थकता नहीं. कहानी हिट होती रही है.

बांद्रा में अपने छोटे-से फ्लैट की खिड़की से बाहर झांकते हुए भारत भूषण उधेड़बुन में खोये दिखते हैं कि जो जीवन वे जी चुके क्या वह सचमुच किसी मतलब का था. वे कहते हैं, "मैंने कहीं पढ़ा था फिल्मोद्योग की यह यात्रा मौन से मौन तक की है. एक मौन तो मूक फिल्मों का प्रतीक है लेकिन दूसरा शर्मिंदगी का, पास में कहने लायक कुछ न होने का." या यों भी कह सकते हैं कि यह यात्रा है—यादगार फिल्मों से न देखने योग्य फिल्मों तक की.

—सलिल त्रिपाठी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

श्रीलंका

करार कामयाबी की राह पर

प्रांतीय परिषदों के चुनावों के बाद पहल अब भारत के हाथ में

श्रीलंका में पिछले पखवाड़े अचानक घटनाक्रम जितनी तेजी से घूमा वह भारत-श्रीलंका समझौते के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण था. नौ महीने तक समझौते की खासी लानत-मलामत होती रही लेकिन अब हालात ऐसे बन रहे हैं जिनसे उसकी सफलता की संभावनाएं दिखने लगी हैं.

सबका श्रेय महारथी राष्ट्रपति जे.आर. जयवर्द्धने को जाता है. सबसे पहले तो सिंहली क्षेत्रों में प्रांतीय परिषद के चुनावों का एक दौर चला जो समझौता विरोधियों के गाल पर तमाचा ही सिद्ध हुआ. फिर सरकार और प्रतिबंधित अतिवामपंथी संगठन जनता विमुक्ति पेरुमना के बीच कथित समझौता हुआ. यह संगठन दक्षिणी श्रीलंका में आतंकवाद का खासा प्रदर्शन कर चुका है.

सरकार ने घोषणा की कि वह पेरुमना पर प्रतिबंध हटा लेगी और उसके गिरफ्तार कार्यकर्ताओं को रिहा कर देगी. यह संगठन हथियार सौंपने, हिंसा त्यागने और राजनैतिक मुख्य धारा में शामिल होने पर राजी हो चुका है लेकिन उस समय सारा उत्साह फीका पड़ गया जब पेरुमना के अध्यक्ष रोहणा विजेवीरा ने किसी भी समझौते से इनकार कर दिया.

इसके बावजूद पेरुमना के साथ समझौते की संभावनाओं से फिलहाल इनकार नहीं किया जा सकता. पिछले पखवाड़े के परिषद चुनावों में पेरुमना को मुंह की खानी पड़ी थी. उसकी धमकी थी कि वोट देने वालों और चुनाव लड़ने वालों की हत्या कर दी जाएगी. हालांकि नौ उम्मीदवारों की हत्या की गई, पर 28.9 लाख वोटरों में से 62 प्रतिशत ने वोट डालकर विमुक्ति पेरुमना के मुंह पर तमाचा जड़ दिया.

इसका श्रेय भी जयवर्द्धने को ही जाता है जो राजनीति में अपनी चालाकियों के लिए खास मशहूर हैं. पेरुमना के विरुद्ध बढ़ती लोगों की नाराजगी को देखते हुए जयवर्द्धने ने परिषद चुनावों की घोषणा कर डाली. उस समय पूरा देश अभिनेता से राजनेता बने विजय कुमार रणतुंगे की हत्या पर शोक में डूबा हुआ था.

परिणामों ने पेरुमना को यह एहसास दिला दिया है कि जनमत तेजी से उनके खिलाफ मुड़ रहा है. इसके अलावा दक्षिणी और पश्चिमी इलाकों में भारतीय शांति सेना की मौजूदगी का एक परिणाम यह हुआ है कि श्रीलंका सेना को दक्षिण में पेरुमना के गढ़ों पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करने का मौका मिल गया है. इस सबके कारण ऐसा लगता है कि पेरुमना के नेता और कार्यकर्ता अब हथियार डालकर कोलंबो सरकार के साथ शांति वार्ता करने को मजबूर होंगे.

भारत इस उम्मीद को नहीं छोड़ सकता कि कोलंबो सरकार तथा पेरुमना के बीच समझौते की संभावना है. यदि ऐसा कोई विश्वसनीय समझौता हो जाता है तो भारत पर तमिल चीतों के साथ ऐसी ही कोई व्यवस्था करने और शांति सेना को किस्तों में वापस बुला लेने का दबाव बढ़ जाएगा. हाल तक तो भारतीय उच्चायोग के अधिकारी यही मानते आ रहे थे कि "जयवर्द्धने शांति सेना की वापसी की मांग तुरंत नहीं करने वाले हैं क्योंकि पेरुमना से निबटने के लिए उन्हें उसकी जरूरत है."

समझौते और घरेलू राजनीति में आए मोड़ की वजह से आज जयवर्द्धने की स्थिति खासी मजबूत हो गई है. चुनावों के बाद समझौता एक कसौटी पर तो खरा उतर गया. जयवर्द्धने ने कहा भी, "पहला राजनैतिक लक्ष्य हासिल कर लिया गया है." समझौते की एक शर्त थी चुनाव—और इस पर जैसे पूरा दारोमदार था समझौते का.

जयवर्द्धने प्रांतीय परिषदों का चुनाव प्रचार करते हुए: अच्छी सफलता

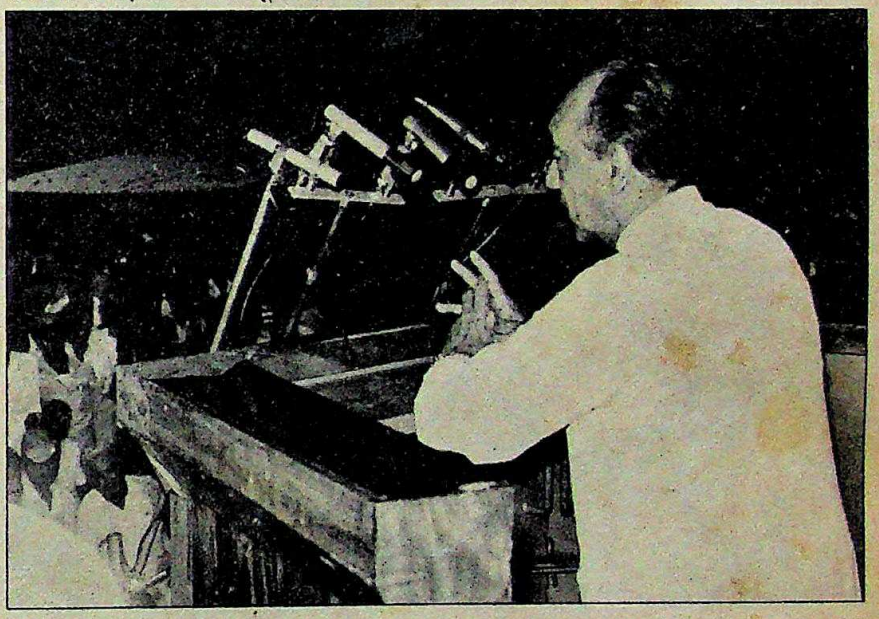

जयवर्द्धने ने कामयाबी से प्रांतीय परिषदों के चुनाव करा जनमत का रुख अपनी ओर कर लिया. समझौते की शर्त थी चुनाव और इसी पर समझौते का दामोदार था.

फिर मुख्य विपक्षी दल श्रीलंका फ्रीडम पार्टी ने इसका बहिष्कार भी किया था. राजनीति के चतुर खिलाड़ी जयवर्द्धने ने विभिन्न चरणों में चुनाव कराने का निश्चय कर लिया.

अतुलतमुदाली ने स्वीकार किया, "नतीजे उम्मीद से कहीं बेहतर निकले." चुनावी नतीजों का इंतजार कर रहे राजीव गांधी इसे 'समझौते के प्रति श्रीलंका की जनता के समर्थन का सबूत' माना.

बहरहाल, चुनावों ने समझौते के संदर्भ में जयवर्द्धने की स्थिति को मजबूती प्रदान की है. यह साबित हो गया है कि:

► चुनाव बहिष्कार और हत्या की

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

धमकियों के बावजूद चुनाव सफल रहे.

► उनकी पार्टी अब बाकी बचे तीन सिंहली प्रांतों में से दो में भी जीत सकती है.

► वे भारत पर और दबाव डाल सकते हैं उन्होंने से तो जरूरत से ज्यादा ही काम पूरा कर दिया. जबकि भारत को तमिल चीतों से पूरी तरह से हथियार डलवाना बाकी है.

► इस दुष्प्रचार की उन्होंने पोल खोल दी कि प्रांतीय चुनावों से देश के टुकड़े हो जाएंगे.

जहां तक उत्तरी और पूर्वी श्रीलंका की बात है, मौजूदा हालात चुनाव लायक नहीं है. युद्धमंत्री रानिल विक्रमासिंघे कहते हैं, "हिंसा में कमी हुई है लेकिन यह खत्म नहीं हुई है. उत्तर में सामान्य स्थिति तो बहाल हो गई है लेकिन पूर्व में भारतीय शांति सेना अभी यह दावा नहीं करती."

शांति सेना की उपलब्धि यह मानी जा सकती है कि उसने तमिल चीतों को छापामार युद्ध करने और फिर व्यक्तिगत हत्याएं करने पर मजबूर कर दिया है. अतुलतमुदाली ने कहा, "छापामार लड़ाई से निबटना तो सेना का काम है ही, लेकिन समस्या का कोई सैनिक समाधान नहीं है. एकमात्र हल यही है कि चीतों को राजनैतिक मुख्यधारा में शामिल होने पर राजी किया जाए."

तमिल चीतों को निशस्त्र करने के लिए सैनिक अभियान तो जारी है ही, भारत सरकार ने 4 फरवरी को उससे 'अनौपचारिक बातचीत' की पहल करके राजनैतिक हल की शुरुआत भी की. तमिल चीते भी सुलह के मूड में दिख रहे हैं.

तमिल चीतों के एक सूत्र ने कहा, "हमने हथियार सौंपने का फैसला कर लिया है. केवल इनकी संख्या के बारे में अंतिम फैसला करना रह गया है." अनुमान है कि उनके पास राइफल, गोला बारूद, राकेट लांचर वगैरह मिलाकर करीब 3,000 हथियार हैं. भारत ने 1,500 राइफलों के सौंपने पर जोर दिया है, जबकि तमिल चीतों का दावा है कि उनके पास केवल 500 राइफलें ही हैं.

'इंडिया टुडे' को पता लगा है कि तमिल चीतों ने दो शर्तें भारत सरकार के सामने रखी हैं— छह महीनों के लिए अंतरिम प्रशासनिक परिषद का गठन जबकि शरणार्थी और दूसरे तमिल राजनैतिक गुट उत्तर-पूर्व में लौट आएं. वे अपने लिए उस राजनैतिक सत्ता की भी मांग कर रहे हैं जिसकी पेशकश उन्हें समझौते के तुरंत बाद की गई थी.

यह दुस्साहसपूर्ण भले लगता हो तथ्य यही है कि वे अभी भी सौदे की स्थिति में हैं. पहली बात तो यह कि अभी भी उन्हें भारी समर्थन प्राप्त है. दूसरी, तमिल क्षेत्रों में राजनैतिक सक्रियता नहीं के बराबर है, और तमिल चीतों के सहयोग के बिना इसे शुरू करना लगभग असंभव ही है. तीसरे, वे हार भले ही गए हों, अपंग नहीं हुए हैं. तमिल चीतों के एक सूत्र का कहना है कि 'चीते मूल रूप से विध्वंस के कलाकार' हैं. उसने कहा, "हम शांति के लिए तो तैयार हैं ही लेकिन विएतनाम जैसी स्थिति का सामना करने की भी तैयारी कर रहे हैं."

लेकिन अंतरिम परिषद के गठन पर समझौते की संभावना खत्म हो गई है. बताया जाता है कि जनवरी में नई दिल्ली में हुई बैठक में राजीव और जयवर्द्धने दोनों ने ही प्रस्ताव का विरोध किया था. चीतों की दूसरी मांग यह है कि प्रांतीय परिषदों के अधिकारों पर फिर बात की जाए. इस पर भारत ने यह कहा है कि पहले तमिल प्रांतीय परिषद के चुनाव जीत लें, तब इस पर बात होगी.

राजीव और जयवर्द्धने दोनों ही उत्तर और पूर्वी प्रांतों में जुलाई तक चुनाव करवाना चाहते हैं. लेकिन जब तक भारतीय शांति सेना वहां से वापसी की प्रतीकात्मक पहल भी नहीं करती तब तक जयवर्द्धने सिंहली मतदाताओं के आगे किस मुंह से बात करेंगे. और सेना तभी हटेगी जब प्रांतीय परिषदों का गठन नहीं हो जाता है.

समझा जाता है कि भारतीय शांति सेना वी. प्रभाकरन को— जहां तक संभव हो जिंदा अन्यथा मजबूरी में मरा—ढूंढ़ निकालने का प्रयास कर रही है. पक्का विश्वास है कि प्रभाकरन का जो असर चीतों पर है, उसकी कोई बराबरी नहीं. उनकी अनुपस्थिति से तमिल चीते लगभग बिखर जाएंगे जिससे भारत की समस्या सुलझ जाएगी. यह पूछने पर कि क्या भारतीय शांति सेना को प्रभाकरन पर गोली न चलाने के निर्देश दिए गए हैं, जनरल अफसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल ए.एस. कलकट ने कहा, "ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया है."

लेकिन सच यह है कि उत्तरी प्रांत में शांति सेना के 'विराट' और 'त्रिशूल' नामक सैनिक कार्रवाइयों का असली मकसद प्रभाकरन को ढूंढ़ निकालना ही था. बहरहाल, श्रीलंका सरकार ने जिस कामयाबी से परिषदों के चुनाव करवाए उसके बाद भारत के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं कि वह तमिल चीतों को युद्धविराम और राजनैतिक समझौते पर रजामंद करे. और यह जुलाई के पहले हो जबकि उत्तरी और पूर्वी प्रांतों में चुनाव कराने की योजना है.

—अनीता प्रताप, कोलंबो में

अतुलतमुदाली: सैनिक समाधान नहीं

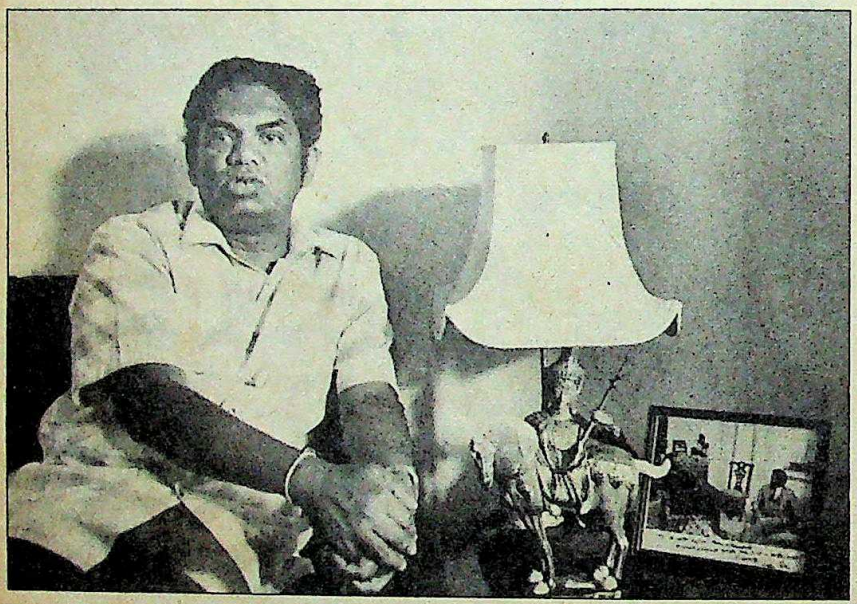

अतुलतमुदाली कहते हैं कि समस्या का कोई सैनिक समाधान नहीं. एकमात्र हल तमिल चीतों को राजनैतिक मुख्य धारा में शामिल होने पर राजी करना है.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दक्षिण भारत परिशिष्ट

आमुख

परंपरा और परिवर्तन का परिदृश्य

बड़े-बड़े बादशाहों की ताजपोशी करने से लेकर उनके ताज धूल-धूसरित करने की क्षमता के दर्प से दीप्त उत्तर भारत के लिए दक्षिण अबूझ पहेली जैसा ही बना रहा है. सत्ता ही जब नियामक हो कई चीजों की, तो दूसरे कई नियामक बहुत पीछे छूट जाते हैं. शायद यही कारण है कि उत्तर ने कभी दक्षिण को गंभीरता से समझने की कोशिश नहीं की.

यों तो किसी समाज को समझने के कई नियामक हैं. प्रस्तुत है दक्षिण भारत को तीन नियामकों—राजनीति, साहित्य और सिनेमा—के जरिये समझने की कोशिश:

दक्षिण भारत को समझने के लिए अन्य तमाम नियामकों में से तीन नियामक चुने गए हैं इस विशेष परिशिष्ट में—राजनीति, साहित्य और सिनेमा. आज के दौर में राजनीति इतनी सर्वव्यापी हो गई है कि वह समाज के प्रायः हर पहलू को प्रभावित करने लगी है. उसकी अनदेखी असंभव है. और अभिव्यक्ति के दो महत्वपूर्ण माध्यम हैं—साहित्य और सिनेमा. साहित्य तो सतत धारा होती है जिसकी जड़ें परंपरा में गहरी धंसी होती हैं. सिनेमा आधुनिक दौर की चीज है लेकिन आज अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम. इन तीनों क्षेत्रों में हुए परिवर्तन का लेखा-जोखा दक्षिण के समाज को समझने में बहुत हद तक सहायक होगा.

जहां तक राजनीति का सवाल है, उत्तर के लिए तो यह सदियों से जैसे शगल की चीज रही है. प्रायः सभी विदेशी शासक विंध्य पहाड़ियों की सीमा तक ही सिमटे रहे. इस सीमा को लांघने की थोड़ी कोशिश बाद के मुगलों ने की लेकिन दक्षिण में राजनीति का दौर अंग्रेजों के आने के बाद और फिर राष्ट्रीय नवजागरण की लहर के साथ शुरू हुआ. उत्तर में अगर नेहरू और पटेल उभरे तो दक्षिण ने राजगोपालाचारी और कामराज सरीखे दिग्गजों को राष्ट्रीय रंगमंच पर स्थापित कर दिया. आजादी के बाद हिंदी विरोध की लहर, और फिर क्षेत्रीय पार्टियों की धूम—दक्षिण का राजनैतिक परिदृश्य इस तरह बदलता रहा. और आज स्थिति यह कि लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी अगर कोई है तो वह दक्षिण की ही है.

किसी समाज को समझने के लिए उसकी भाषा, उसके साहित्य के विकास की समझ राजनीति की समझ से कम मूल्यवान नहीं होती. साहित्य, कला, संस्कृति, दर्शन आदि के मामलों में उत्तर और दक्षिण के बीच आदान-प्रदान का क्रम सतत चलता रहा है. चारों दक्षिण भाषाओं के साहित्य का विकास दूसरी भारतीय भाषाओं के विकास से अलग नहीं रहा है. आज दक्षिण की भाषाओं का नया सृजन परंपरावाद को छोड़ प्रयोगों की क्रांतिकारी राह पर चल पड़ा है.

दक्षिण में हिंदी का विरोध भले होता हो लेकिन यह भी सच है कि आज सिनेमा-टीवी ने इस विरोध की धार को बहुत हद तक कुंद किया है. हिंदी सिनेमा पर आज अगर दक्षिण भारतीय अभिनेत्रियों का राज है तो खुद दक्षिण का सिनेमा जगत बदलाव के दौर से तालमेल बिठाने में लगा है. फंतासी और रूमानी फिल्मों की जगह यथार्थपरक फिल्मों ने ली है. साथ-साथ हिंसा और सेक्स का भी बोलबाला बढ़ा है. दक्षिण भारतीय सिनेमा का कायाकल्प हो गया है.

इस विशेष परिशिष्ट में दक्षिण भारत में इन तीन क्षेत्रों—राजनीति, साहित्य और सिनेमा—में हो रहे परिवर्तनों के जरिये उस समाज को समझने और उसका परिचय कराने की कोशिश की गई है.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दक्षिण भारत परिशिष्ट

राजनीति

उत्तर के वर्चस्व को क्षेत्रीय ताकतों की चुनौती

भारतीय राजनीति के रंगमंच से नेहरू और पटेल सरीखे नेताओं की विदाई के बाद राजीव और बूटा जैसों के विराजमान हो जाने से एक युग अब आखिरी सांसें गिन रहा है. बागडोर ऐसे लोगों के हाथों में आ गई है जिनकी अपनी कोई हस्ती नहीं, माद्दा नहीं. भारतीय नक्शे के ऊपरी हिस्से यानी उत्तर भारत में तो सब कुछ साफ-साफ दिख रहा है, लेकिन दक्षिण भारत अभी भी इडली, सांभर और फिल्मी मुख्यमंत्रियों के कारण अबूझ पहेली बना हुआ है.

हेगड़े की असली ताकत उन्हें मिली कांग्रेसी जन्मघुट्टी है. राज्य में उनका स्वागत व्यक्ति के नाते है, राजनैतिक प्रतिनिधि के रूप में नहीं. पर क्या निजी करिश्मा उनके सफेद कुर्ते पर लगे दाग मिटा पाएगा?

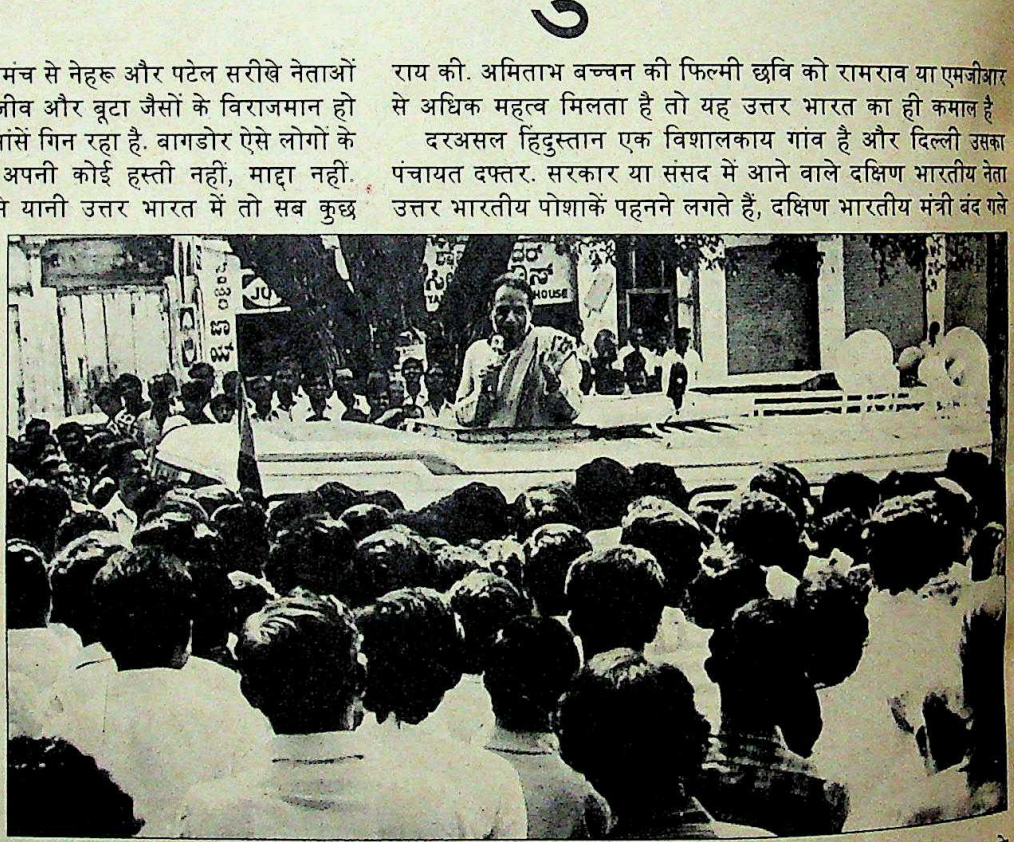

कृष्ण मेनन और कामराज जैसे महारथियों के दिन फाख्ता हुए, अब मूपनार और करुणाकरन जैसों की बिरादरी सर्वेसर्वा बन चुकी है. राजगोपालाचारी के दिन लद गए, अब जयललिता, जानकी का जमाना है. तेलंगाना आंदोलन के खून और आंसुओं की जगह गणेश चतुर्थी पर हुए दंगे के खून की लाली फैल गई है.

लोगों को रामराव की फिजूलखर्ची और एमजीआर के भ्रष्टाचार से ज्यादा इस बात से भले ही अधिक सदमा पहुंचता हो कि बीरबहादुर सिंह सरकारी विमान का इस्तेमाल अपना पायजामा मंगाने के लिए करते हैं, पर यह भी सच है कि जयललिता और रामराव के नाटकीय लटकों पर जो ठहाके लगते हैं वैसे ठहाके लगवा लेना न तो किसी के.के. तिवारी के बस की बात है और न कल्पनाथ राय की. अमिताभ बच्चन की फिल्मी छवि को रामराव या एमजीआर से अधिक महत्व मिलता है तो यह उत्तर भारत का ही कमाल है

दरअसल हिंदुस्तान एक विशालकाय गांव है और दिल्ली उसका पंचायत दफ्तर. सरकार या संसद में आने वाले दक्षिण भारतीय नेता उत्तर भारतीय पोशाकें पहनने लगते हैं, दक्षिण भारतीय मंत्री बंद गले का कोट पहनते हैं और सांभर के स्वाद वाली हिंदी बोलते हैं. उत्तर के रंगढंग में रच-बस कर वे जैसे उसके सदस्य बन जाते हैं.

लेकिन उत्तर वालों के लिए दक्षिण एक पहेली और उसकी राजनीति एक रहस्य ही है. तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में अब स्थानीय दबाव अधिक प्रभावकारी हो रहे हैं और कांग्रेसी जन्मघुट्टी पिए बिना नेता बने लोगों की तादाद बढ़ रही है. दक्षिण न केवल कांग्रेसी राष्ट्रवाद की असफलता का प्रतीक बन चुका है बल्कि इस पार्टी को वहां अब उत्तर की एक क्षेत्रीय पार्टी माना जाने लगा है. उत्तर की दादागीरी को शुबहे की आंखों से देखने वाले दक्षिण ने उसे नर्स और स्टेनोग्राफर तो सप्लाई किए मगर उसकी कांग्रेस और उसकी रुपहली खादी से मुंह फेर लिया. कर्नाटक ही ऐसा राज्य है जहां कांग्रेसी मानसिकता का बोलबाला है (जनता और कांग्रेस में आखिर कौन-सा बड़ा अंतर है?). वहां भी हेगड़े के रूप में कन्नडिगा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भावनाएं मजबूत होने लगी हैं. हेगड़े जब भी राज्य के गांवों या कस्बों में जाते हैं तो उन्हें जो स्वागत मिलता है वह व्यक्ति का होता है न कि किसी राजनैतिक विचारधारा का. मगर यह सब भी अब पुराना पड़ रहा है. जिस तरह एक के बाद दूसरा घोटाला बंगलूर की चूलें हिला रहा है उसे देखकर तो सोचना पड़ रहा है कि हेगड़े का निजी करिश्मा उनके सफेद कुर्ते पर लगे दाग मिटा पाएगा भी या नहीं.

दक्षिण को न समझ पाने की कांग्रेसी अक्षमता का ही परिणाम है कि पुजारी और उनके चेले जलप्पा कांड को कर्नाटक में जनता सरकार की असफलता मान बैठते हैं. मगर हेगड़े भी खुद अपने बुने जाल में उलझ रहे हैं. वे क्षेत्रीय नेता होते हुए भी एक राष्ट्रीय बल्कि उत्तर भारतीय छवि बनाने पर तुले हुए हैं. इस बात को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है कि उत्तर में गरचा कांड भले ही कुछ नुकसान पहुंचाए बिना खत्म हो जाता हो पर दक्षिण में रशीद हत्याकांड जैसी घटना भी सरकार की नींव हिलाकर रख सकती है. यहां तक कि मोइली टेप कांड जो गुल दक्षिण में खिला सकने की औकात रखता है वह उत्तर में वी.पी. सिंह के बोफोर्स कांड के बूते के बाहर की चीज है. ऐसे में अगर हेगड़े की सरकार गिरती है तो इसका थोड़ा-सा अर्थ कांग्रेसी मानसिकता की हार ही माना जाएगा क्योंकि लड़े की असली ताकत तो वह कांग्रेसी जन्मघुट्टी है जो उन्हें अपने राजनैतिक जन्म के समय पीने को मिली थी.

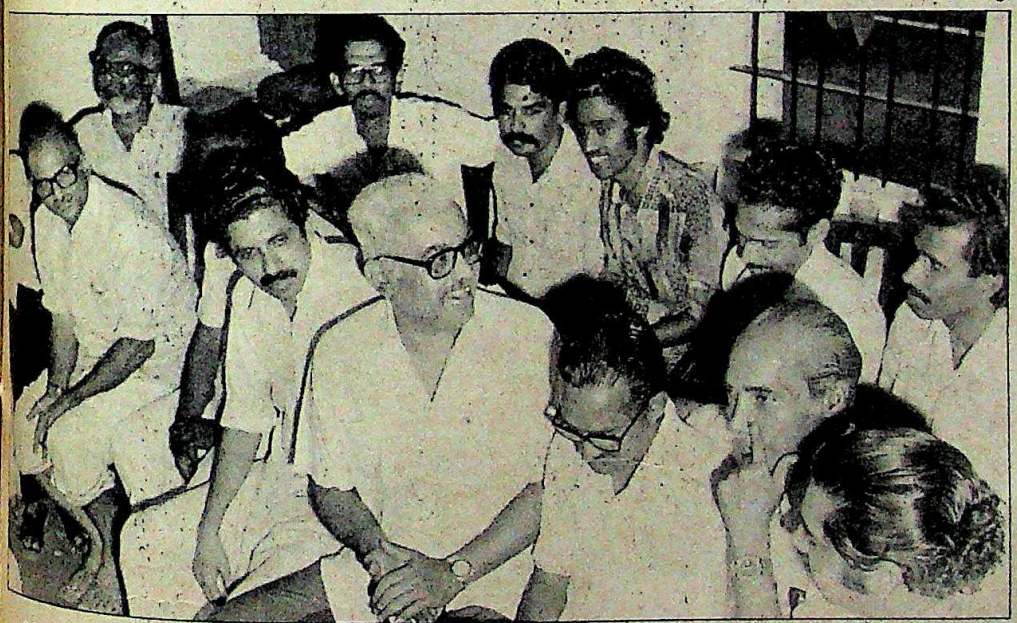

नयनार की मार्क्सवादी सरकार के वर्ग शत्रु हैं पर्यावरणवादी और पुजारी. पार्टी के बुद्धिजीवी मंदिरों में तैनात हो रहे हैं और साम्यवादी विधायक सबरीमाला की तीर्थयात्रा पर दाढ़ी बढ़ा कर जाते हैं

हेगड़े सरकार तो अपना अस्तित्व बचाए रखने में सफल रही लेकिन केरल में कांग्रेस ने बहुत बड़ा खेल खेला. एक समय था जब कांग्रेस को उदारपंथी उच्चवर्गीय समाज का प्रतिनिधि माना जाता था. पर अब इस बात से किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए कि अपने आखिरी दिनों में यह पार्टी अल्पसंख्यकों को ही एक-दूसरे से लड़ाने पर तुल गई है. परिणाम यह है कि ढेरों केरल कांग्रेस कुकुरमुत्तों की तरह उग आई हैं. लेकिन आम मलयाली अब समझदार हो चुका है. खाड़ी में कमाए गए पैसे ने उसे उन रईसजादों से भी अधिक अमीर बना दिया है जिनके लिए उसके बाप-दादा नावें बनाया करते थे. शिक्षा ने उसे बराबरी के वे अधिकार दिला दिए हैं जो उसके पिता के लिए सपने थे. और साम्यवाद जब केरल में पहुंचा तो उसने अपनी लोककथाएं बनाईं, जन-जीवन को नए ढंग से प्रभावित किया. ई.एम.एस नंबूदिरीपाद जैसे ऊंची जाति के मानवतावादी नेता जिन्होंने अपने रैयतों को बराबरी का दर्जा दिया, इसी तरह ए.के. गोपालन और दामोदरन जैसे नेता जिन्होंने अपनी जिंदगी को पुलिस से छिपते-छिपाते तराशा— सभी के किस्से चर्चित हो गए. कम्युनिज्म के साथ ही एक नए साहित्य और उपाख्यानों ने जन्म लिया और वायलार के गीत लोगों की जुबान पर चढ़ गए.

वक्त के साथ-साथ बड़े-बड़े दिग्गज ढहते चले गए. केरल के मूर्तिभंजक धीरे-धीरे खुद ही मूर्तियां बनते चले गए. स्थानीय दबावों ने कम्युनिज्म के ढेरों संस्करण पैदा कर दिए. नंबूदिरिपाद को मुस्लिम लीग की जरूरत आन पड़ी और उससे गले लगकर सांप्रदायिक कम्युनिस्ट पार्टी ने चुनाव जीत लिया. फिर अचानक ही वे धर्मनिरपेक्ष हो गए और मुसलमानों से नाता तोड़कर फिर चुनाव जीत लिया. अब पुलिस के साथ शासन का कोई टकराव नहीं था बल्कि कम्युनिस्ट फलसफे के मुताबिक समाप्त होने के बजाय शासन और मजबूत होता चला गया और पुलिस इस साम्यवादी व्यवस्था का एक अभिन्न अंग बन गई. उधर सीटू मानो हत्या का पर्याय बन गई. यहां तक कि मुख्यमंत्री नयनार भी अपनी सीधी-सादी छवि के बावजूद तब मुसीबत में पड़ गए जब एक स्थानीय अखबार ने पालघाट में उनकी विशाल जायदाद का भंडाफोड़ कर दिया. विधानसभा में किसी गरमागरम बहस के दौरान नयनार अपने विरोधियों को गुस्से भरी नजरों से देखते हैं. लेकिन छोटे दर्जे के कामरेड अपने साथी राघवन की तरह धोती उठाकर गाली-गलौज करते हुए मार्शल द्वारा घसीटकर बाहर ले जाते देखे जा सकते हैं. आज सरकार भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का दावा करती है और इसमें शक नहीं कि दलाल लोग अब सचिवालय के गलियारों में घूमते हुए नहीं देखे जा सकते. पर यह भी सच है कि अब उन्होंने अपना अड्डा पार्टी कार्यालय को बना लिया है.

त्रिवेंद्रम में सचिवालय के बाहर लाल झंडों वाली दुकानें सजी रहती हैं जहां लोग साफ-सुथरे कपड़े पहनकर धुंआ उगलते रहते हैं. यह केवल मार्क्सवाद का ही प्रताप है कि हड़ताली खोमचे वालों का विरोध इतना साफ-सुथरा रूप ले सकता है. अब कम्युनिस्टों के वर्ग शत्रुओं में न पुलिस गिनी जाती है और न शासन. इस श्रेणी में अब पर्यावरणवादी और पुजारी तबके के ही लोग बचे हैं. मजेदार बात तो यह है कि यहां मार्क्सवादी सरकार अब अपने पार्टी बुद्धिजीवियों को मंदिर कमेटियों में तैनात करती है और जब पार्टी के विधायक सबरीमाला की तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो वे बाकायदा दाढ़ी भी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बढ़ाते हैं और ब्रह्मचर्य का भी पालन करते हैं.

अपने खुरदरे खादी चरित्र के लिए मशहूर कांग्रेस पार्टी ने भी मार्क्सवाद को उसी की शैली में पटखनी देने की कोशिश की है. आरक्षण की नीति अपनाने से निचली जातियों के लोगों को सरकार और अफसरशाही में खास महत्व मिला है. परिणामस्वरूप अर्द्ध-शिक्षित अराजपत्रित कर्मचारियों का एक अच्छा-खासा वर्ग वहां खड़ा हो चुका है. इस सबसे बेखबर पूर्व मुख्यमंत्री करुणाकरन अपनी तेज रफ्तार विदेशी कारों में राज्य की तंग सड़कें नापते रहे और एंथनी व दूसरों के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहे. यह कमाल केवल केरल जैसे राज्य में ही देखा जा सकता है कि नवाब राजेंद्रण जैसा पत्रकार मुख्यमंत्री के खिलाफ यातायात के लिए खतरा होने का आरोप लगाकर अदालत में मुकदमा ठोक दे.

जब राज्य में संरघ्र घाटी (साइलेंट वैली) का मामला उठा और उसने राष्ट्रीय विवाद का रूप ले लिया तब कथित टिंबर तस्कर और सत्ताधारी पार्टी के नेता इब्राहिम सुलेमान सैत ने पर्यावरणवादियों का मजाक उड़ाया. एक दलील थी, "कौन कहता है जंगल काटने से मानसून नहीं आता? अरब सागर में कहां पेड़ लगे हैं, वहां क्या बारिश नहीं होती?"

शासन के आसपास छुटभैयों की लगातार बढ़ोतरी होने लगी और उनकी लोकप्रिय नीतियों का बुखार तुरतफुरत फायदों के दरवाजे खोलने लगा. देश के सबसे अधिक शिक्षा प्रसार वाले राज्य में भी सांप्रदायिक आधार पर विश्वविद्यालय खड़े होने लगे. मलयाली जनता की छवि न तो संघीय बन पा रही थी और न राष्ट्रीय. मलयाली एक स्थानीय हस्ती से आगे नहीं बढ़ पा रहा था. ऐसे में क्षेत्रवाद का पनपना स्वाभाविक ही था. देखते-देखते वोटों का फैसला जातीय आधार पर होने लगा. ऐसे में हैरानी की एक बात यह है कि मलयाली पहचान और क्षेत्रवाद के आंदोलन को नक्सलवादियों से भी प्रोत्साहन मिल रहा है. यहां महाराजा त्रावणकोर किसी मुख्यमंत्री से भी ज्यादा प्रभाव रखता है.

राज्य की सीमा के उस ओर तमिलनाडु में एक आप्रवासी मलयाली एमजीआर का कहर अभी हाल ही में समाप्त हुआ है. पेरियार और अन्नादुरै द्वारा द्रविड़ों के नाम पर शुरू किया गया आंदोलन अब अपने हास्यास्पद अंत की ओर बढ़ रहा है. अपने उच्चवर्गीय ब्राह्मणत्व के बावजूद राजगोपालाचारी और कामराज की एक राष्ट्रीय दृष्टि थी जिसे न तो उत्तर के शासक पचा पाए और न ही दक्षिण के निचले वर्गों ने अपनाया. हिंदी विरोधी और उत्तर विरोधी आंदोलन वास्तव में उच्च वर्ग के खिलाफ एक क्षेत्रीय द्रविड़ आंदोलन था और इसकी पेरियार अन्ना लहरों ने कामराज जैसे दिग्गजों को भी उखाड़ फेंका. करुणानिधि जैसे नेता भी अनपढ़ तमिल की अतिभावुकतावादी प्रकृति और सांमती न्याय में उसकी गहरी आस्था को समझ नहीं पाए. ऐसे में अत्याचारी जमींदार वर्ग के खिलाफ तलवार उठाकर न्याय हासिल करने की एमजीआर शैली ने अपना जादू दिखाया और तमिल सिनेमा के माध्यम से निम्नवर्गीय तमिल को नया मसीहा मिल गया.

मगर दुर्भाग्य से एमजीआर कुल मिलाकर एक ऐसे देवदूत के स्तर से आगे नहीं बढ़ पाए जो अपनी छवि चमकाने के लिए तैयार की गई पब्लिसिटी रणनीति के तहत लोगों को नकद और दूसरी सहायता बांटा करता था. इस तरह यह द्रविड़ आंदोलन एक ऐसे फिल्मी अभिनेता के हाथों में समाप्त हो गया जिसे द्रविड़ों की पहचान की बस उतनी ही चिंता थी जितनी किसी दूसरे मलयाली को हो सकती है. उधर वास्तविक द्रविड़ नेता करुणानिधि की हालत यह रही कि उन्हें अपने चाहने वालों की श्रद्धा तो मिली लेकिन एमजीआर के चाहने वालों ने भी उनकी नाक में दम किए रखा. यही कारण है कि हिंदी विरोधी आंदोलन तमिलनाडु में असफल हुआ और कांग्रेस के साथ एमजीआर वह समझौता करने में कामयाब हुए जिसमें करुणानिधि को मुंह की खानी पड़ी.

इसी बीच टीवी के हिंदी अभियान ने रविवार की हिंदी फिल्म, बुनियाद और रामायण के माध्यम से हिंदी विरोधी तमिलों के जोश की बची-खुची हवा भी निकाल दी. उधर श्रीदेवी और भी हिंदी सिनेमा के रास्ते अपनी राष्ट्रीय छवि बनाई. श्रीदेवी और जयप्रदा की पंजाबी छवि देखते-देखते उस ऊंचाई तक जा पहुंची जो तमिलनाडु में एमजीआर की थी. मगर एमजीआर को इसकी क्या परवाह. उनकी फिल्में 10 साल बाद भी 'शोले' के मुकाबले अधिक लोकप्रिय बनी रहीं. जिस समय रामावरम गार्डन्स से दूर अपने घरों में बैठे तमिल परिवार दूरदर्शन पर 'हम लोग' के चरित्रों के साथ हंस या रो रहे होते उस समय एमजीआर अपने डिश एंटिना की

एमजीआर देवदूत थे जो अपनी छवि चमकाने के लिए सहायता बांटते थे. द्रविड़ आंदोलन ऐसे अभिनेता के हाथों मिटा जिसे द्रविड़ों की पहचान की उतनी ही चिंता थी जितनी किसी मलयाली को

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

चुनौतियों का प्रबंध ही हमारा काम

समुदाय- उन्मुखी व्यापारी घराने के रूप में जहां लोगों की प्रेरणा ही सब कुछ है, मैसूर सेल्स इंटरनेशनल लिमिटेड ने लागत का ध्यान रखने वाले व्यापारी दृष्टिकोण के साथ सामाजिक उद्देश्यों को एक करने की योग्यता हासिल की है। हम उचित प्रबंध तरकीबों, कौशल और कल्पना से समस्याओं का समाधान करते हैं।

चाहे नहाने का साबुन बाजार में लाना था। या डिटर्जेन्टों की बिक्री व्यवस्था करनी थी। या कर्नाटक सरकार के लॉटरी टिकट बेचने थे, या लेखक नोटबुकें बनाकर उनकी बिक्री व्यवस्था करनी थी, **एमएसआईएल** अपने वादे को बखूबी पूरा करती रही बल्कि उससे भी दो कदम आगे रही। बंगलौर एयर कार्गो कॉम्पलेक्स के बन जाने से **एमएसआईएल** ने अनेक विशिष्ट क्षेत्रों में सेवाकारी सुविधाएं आपकी सेवा में पेश कीं।

कंपनी की शुरुआत से ही **एमएसआईएल** विदेशों में व्यापार करती आई है तभी तो आज **एमएसआईएल** उसके कामों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में मशहूर है और नए उत्पादों के निरंतर विकास तथा संभाव्य बाजार का पता लगाने में उसकी क्षमता सर्वत्र जानी-मानी है।

एमएसआईएल सिर्फ उत्पाद या सेवाओं तक सीमित नहीं है। **एमएसआईएल** तो लोग हैं। अनुशासन है और व्यावसायिक है। आदतन, **एमएसआईएल** सदा नई चुनौतियों की तलाश में रहती है और उनके मौलिक तथा नए-नवेले समाधान ढूंढ़ निकालती है।

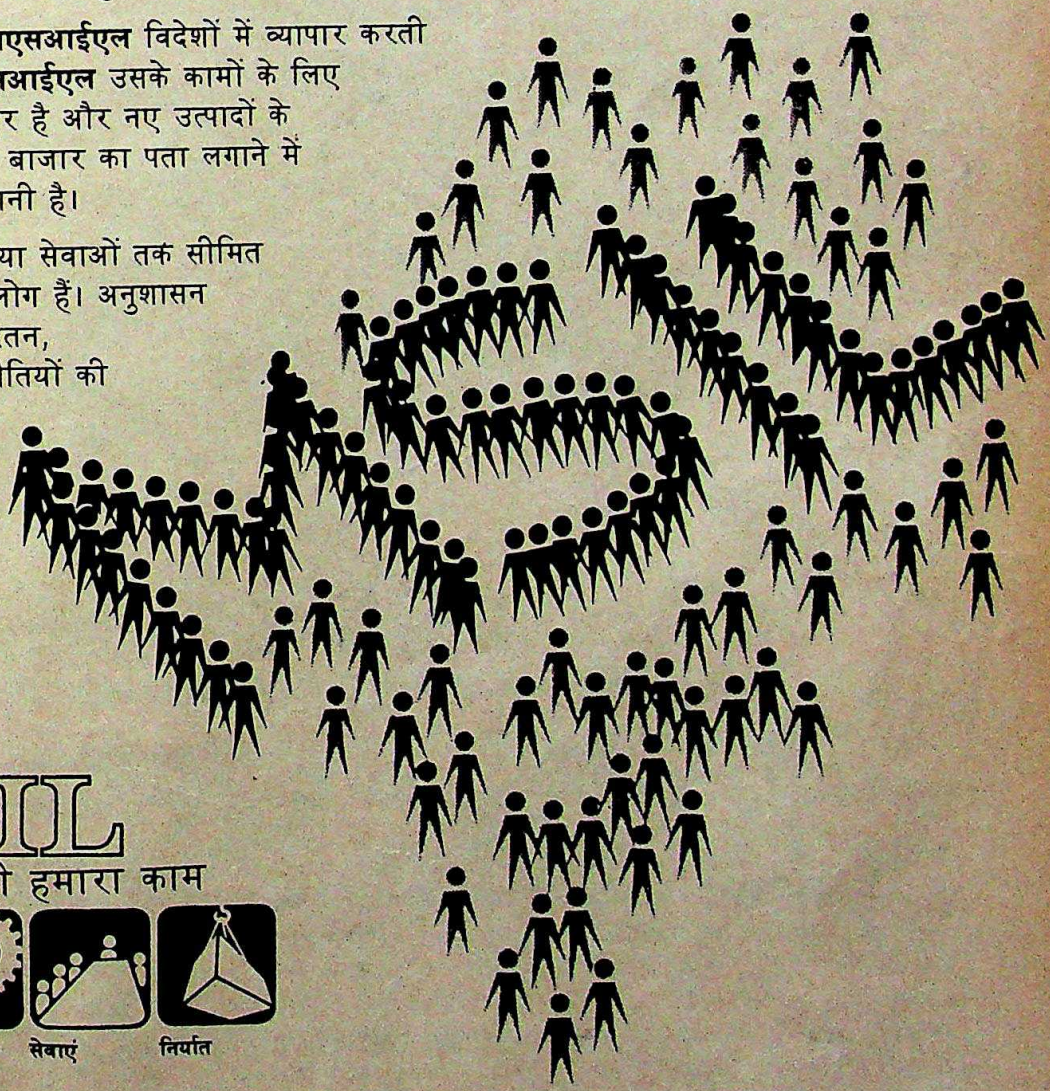

MSIL

चुनौतियों का प्रबंध ही हमारा काम

उपभोक्ता उत्पाद | औद्योगिक उत्पाद | सेवाएं | निर्यात

मैसूर सेल्स इंटरनेशनल लिमिटेड
एमएसआईएल हाउस
36 कनिंघम रोड, बंगलौर 560052
बम्बई • कलकत्ता • दिल्ली • मद्रास • लंदन-(यूके)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गीयर्स औरों से ज़्यादा

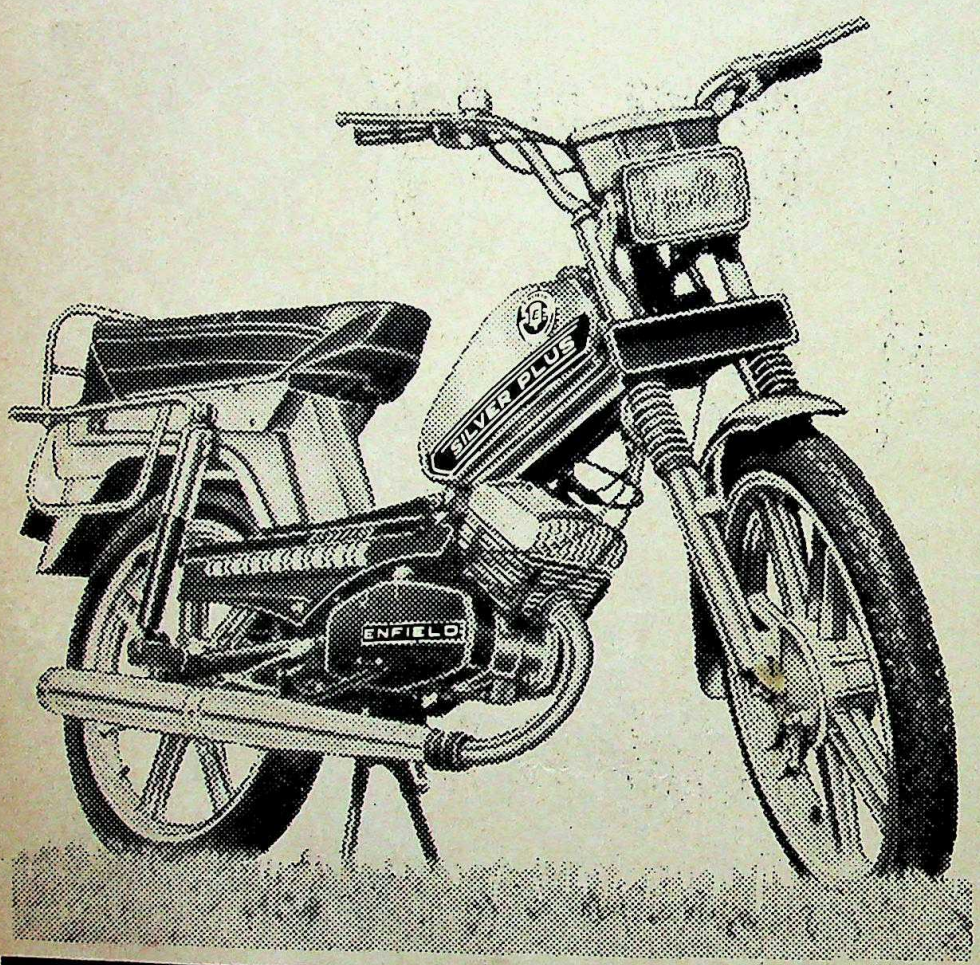

सिल्वर प्लस
एक विशिष्ट बाइक
इसका एक-एक गुण और लक्षण सिल्वर प्लस को अन्य मोपेडों से कहीं अलग प्रतिष्ठित करता है।

- अधिक इंधन बचत और स्मूद ट्रॅन्समिशन (सुगम संचरण) के लिए टिवन केबल सिस्टम के साथ तीन गीयर।
- किक स्टार्टर। पेडल करने या धक्का देने की जरूरत नही।
- सुरक्षित सवारी और तुरन्त रोकने के लिए १२० मि.मी. डायामीटर के ब्रेक ड्रम।
- दो के लिए बड़ी व आरामदेह गद्दी।
- मज़बूत और टिकाऊ प्रेशर डाईकास्ट एल्युमिनियम के पहिए।
- मज़बूत और टिकाऊ हेवी ड्यूटी सुदृढ ढांचा।
- तेज़ पिक-अप और ६० कि.मी. प्रति घंटे की अधिकतम गति वाला ५० सीसी का २.८ बी एच पी इंजन
- इंजन को दीर्घायु प्रदान करने के लिए हाई क्रोम प्लेट एल्युमिनियम बैरल।
- ७० कि.मी. प्रति लीटर इसको किफायती बनाता है।
- बिना झटके की सवारी के लिए ६० मि.मी. स्ट्रोक वाला हाइड्रॉलिक सस्पेन्शन व स्विंग आर्म द्वारा बिठाया गया पिछला शॉक एबसॉर्बर।
- अधिक स्थिरता के लिए ६५ कि.मी. स्ट्रोक वाला आगे का टेलिस्कोपिक फोकी।
- जर्मन तकनीक और एनफील्ड की निपुणता सिल्वर प्लस को एक विशेष अनुभव बना देती है।
- कई रंगों में उपलब्ध।

सिल्वर प्लस

ENFIELD

असली टू-सीटर

ऐसी सवारी जब मिले. महज मोपेड से काम न चले.

हमेशा एनफील्ड के अतिरिक्त पुर्जे ही इस्तेमाल कीजिए।

CC-0, In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मदद से टीवी पर बीबीसी के कार्यक्रम देख रहे होते.

लोगों को याद है कि एमजीआर की शवयात्रा के समय उनकी पत्नी जानकी लोगों को सुनाने के लिए तमिल में विलाप कर रही थीं जबकि सचाई यह है कि घर में वे लोग आपस में मलयालम में बात किया करते थे. इसी तरह जयललिता ने भी जब एमजीआर की काल्पनिक चिता में कूदने की इच्छा जाहिर की तब मदुरै में मौजूद भीड़ ने चिल्लाकर कहा— "नहीं, नहीं." तब जयललिता ने सवाल किया, "मैं तो अनाथ हो गई. अब मैं कहां जाऊं." इस पर भीड़ ने चिल्लाकर आश्वासन दिया, "हम तुम्हारे साथ हैं."

राजगोपालाचारी और कामराज से लेकर जयललिता और जानकी तक के इस यात्रा इतिहास ने तमिलों के साथ अच्छा-खासा मजाक किया है. इस पर द्रविड़ों के लिए संघर्ष में अपनी ठुकाई करवा चुके नेता करुणानिधि चुटकी लेते हुए कहते हैं, "अन्नाद्रमुक के द्रविड़ों का नेतृत्व दो ब्राह्मण महिलाओं के हाथ में है."

एमजीआर की मृत्यु के दिन अन्नाद्रमुक के राजनैतिक लोकाचार का घड़ा सरे बाजार फूट गया. भीड़ जब हिंसा पर उतारू हो गई तो उसकी असहायता खुलकर सामने आ गई. दूसरे फिल्मी सितारों के होर्डिंग तहस-नहस कर दिए गए. एमजीआर की मृत्यु के साथ ही वह छवि सुबह की ओस की तरह गायब हो गई जिसे पटकथा लेखकों और फिल्म निर्देशकों ने बड़े जतन से सजाया-संवारा था.

तमिलनाडु का रंगमंच एकदम बदल चुका है. अब सत्ता को तुरत-फुरत हथिया लेना मुद्दा नहीं रह गया. अब मुद्दा एक नए लोकाचार को स्थापित करने का है. जानकी सत्ता में आकर भी यह नहीं कर पाएंगी और जयललिता-कांग्रेस गठबंधन भी अब तक की सबसे 'संभ्रांत' सरकार ही मानी जाएगी. और अगर करुणानिधि सत्ता में आते हैं तो उनके लिए भी पहले जैसा हिंदी विरोधी और केंद्र विरोधी वातावरण तैयार कर पाना असंभव होगा क्योंकि श्रीदेवी की खूबसूरत टांगों, प्रभाकरन की अस्पष्ट रणनीति और अरुण गोविल की छवि ने हालात को हमेशा के लिए बदल डाला है.

आंध्र एक ऐसा राज्य है जहां सिनेमा आज भी अपना प्रभाव बनाए हुए है. फिल्मी सितारे और आकाश को छूते हुए उनके ऊंचे-ऊंचे होर्डिंग जनमानस पर गहरी छाप जमाए हुए हैं. तेलुगु पहचान जैसे पुराने मुद्दे रामराव की अपनी फिल्मी छवि के साथ एक हो चुके हैं. केरल को छोड़ शेष तीनों दक्षिणी राज्यों में पौराणिक चरित्रों के प्रति अगाध श्रद्धा है. किसी जमाने में देश को झकझोर देने वाला तेलंगाना आंदोलन उलटे कम्युनिस्टों के सिर पर आन पड़ा है. जिन इलाकों में कभी उनकी तूती बोलती थी आज वहां के लोग तेलुगु देशम को वोट देते हैं. एक जमाना था जब सामंती रियासतों में कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों को राजा की तरह पूजा जाता था लेकिन अब वक्त बदल गया है. अब जमाना राजाओं का नहीं रहा, देवताओं का हो गया है. और वह भी फिल्मी देवताओं का.

असंख्य तेलुगु फिल्मों में दैवी भूमिकाएं निभा चुके रामराव का सपना तेलुगु रामराज्य की स्थापना करना है. अपनी पुरानी फिल्मों में जो मुकुट वह राम की भूमिका में पहना करते थे वह जैसे उन्होंने अरुण गोविल को उपहार के तौर पर दे दिया है जिसे अरुण ने अयोध्या कांड के दौरान पहना. अपनी बातचीत में पौराणिक संदर्भों का इस्तेमाल करना रामराव की शैली बन चुकी है. वे अक्सर कहा करते हैं, "मैं राम हूं और आंध्र रामराज्य है. तुलसीदास तो केवल पटकथा लेखक ही हुए हैं."

उत्तर ने अपनी अज्ञानता और सत्ता मद के कारण दक्षिण को हमेशा ही एक क्षेत्रीय परीलोक की तरह उपहास की नजर से देखा है. जिस तरह एक आम उत्तर भारतीय यह मानकर चलता है कि दक्षिण का मतलब है मद्रास, और दक्षिण भारतीय केवल इडली, डोसा और सांभर खाकर ही जिंदा रहते हैं उसी तरह दक्षिण भारत के गांवों के लोग यही मानकर चलते हैं कि सब पंजाबी सरदार जी होते हैं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में केवल डाकू रहते हैं और दिल्ली में कोई महिला सुरक्षित नहीं है. उत्तर ने स्वयं को अपने जातिवाद और भाषायी दायरे में बांध लिया तो इसके जवाब में दक्षिण ने भी खुद को सत्ता की संवेदनशीलता के खोल में खींचकर अपनी एक मासूम राजनैतिक छवि पेश कर दी. इस दूरी और अज्ञानता से जो कुछ पैदा हुआ वह किसी भारत महोत्सव के लिए कई प्रतीक जुटा सकता है— दक्षिण का मतलब है हाथी और कथकली नर्तक और उत्तर का मतलब है राजस्थानी लहंगे के घेरे में नाचती महिलाएं और पगड़ी पहनने वाला कुम्हार. ज्यों-ज्यों यह दूरी बढ़ती जाएगी ये प्रतीक ही एक-दूसरे की दुर्भाग्य भरी पहचान बनकर रह जाएंगे. जय हिंद!

—रविशंकर

कई तेलुगु फिल्मों में दैवी भूमिकाएं निभा चुके रामराव का सपना तेलुगु रामराज्य की स्थापना करना है. वे अक्सर कहते भी हैं, "मैं राम हूं, आंध्र रामराज्य. तुलसीदास तो सिर्फ पटकथा लेखक हैं"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हर कोई चाहे न्यूट्रिन ट्विंक

- ऑरेंज
- लेमन
- मैन्गो
- पाइनेपल
- ग्रेप

ट्विंक

सॉफ्ट ड्रिंक कॉन्सन्ट्रेट

नयी मजेदार "स्वाद बहार"

nutrine®

ACIL/056/88-Hin

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

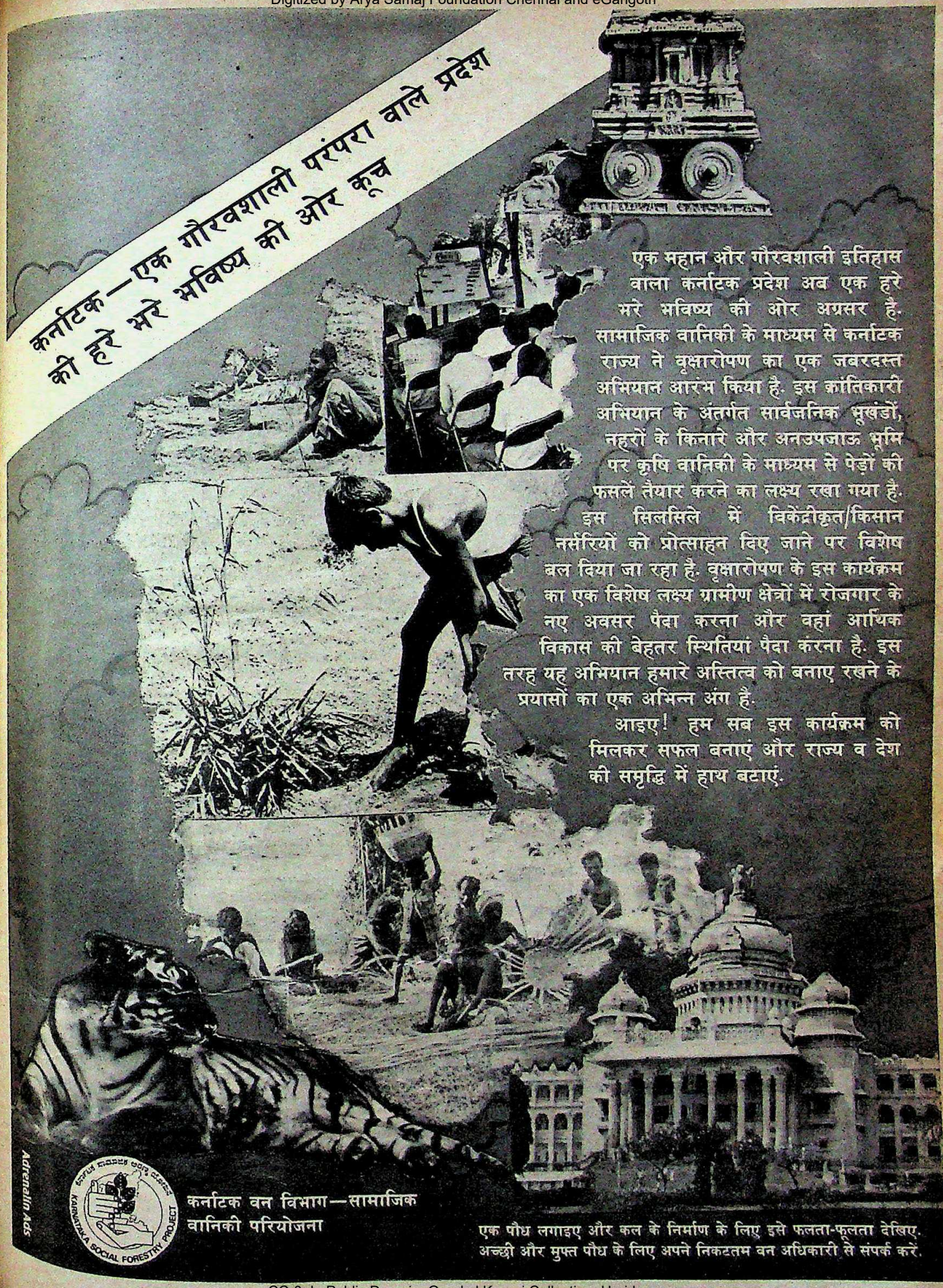

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

साहित्य

नया सृजन प्रयोगों की क्रांतिकारी राह पर

बाहर से आए आर्यों ने यहां के निवासी द्रविड़ों को परास्त किया, उन्हें विध्याचल के दक्षिण में धकेल दिया, उनकी संस्कृति और भाषा पर प्रभुत्व कायम करने के लिए दक्षिण भारत में संस्कृत भाषा साहित्य के केंद्र स्थापित किए तथा उन पर धौंस-धमक से संस्कृतवाद, ब्राह्मणवाद थोप दिया; आर्यो ने द्रविड़ और कोल सभ्यता को बरबाद किया; आर्य परिवार तो इंडो-यूरोपियन परिवार की एक शाखा है जबकि द्रविड़ परिवार शक परिवार से संबद्ध है; आर्य भाषा, द्रविड भाषा और कोल भाषा परिवार एक दूसरे से सर्वथा अलग हैं—यह है वह वर्गीकरण जिसे आज भी सराहा जाता है.

पर सच क्या यही है? ब्रिटिश साम्राज्यवादी तथा कुछ पश्चिमी नस्लवादी अलगाववादी शक्तियों ने भारत को तोड़ने की तैयारी के तहत भारतीय भाषाओं का यह जो वर्गीकरण किया है, सर्वथा भ्रामक और अवैज्ञानिक है. जर्मन विद्वानों ने अनुमान लगाया कि जैसे ऐंगल और सैक्सन कबीलों ने केल्त सभ्यता को मिटाया, भ्रष्ट किया वैसे ही भारत में आर्यों ने द्रविड़ सभ्यता को लील लिया. इसी रणनीति के तहत 19वीं शताब्दी में कोल्डवेल द्रविड़ भाषा परिवार को शक भाषा परिवार से अलग कर देते हैं और 20वीं शताब्दी में भाषा विशेषज्ञ बरो साहब उसे फिनोउग्नियन परिवार से संबद्ध कर देते हैं. सच तो यह है कि ये तमाम कोशिशें भारतीय भाषाओं में प्रादेशिकता पैदा करने की सोची-समझी कार्यपद्धति के ही अंग हैं.

हकीकत में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम इन चारों दक्षिण भाषाओं का साहित्य अपने विकास में दूसरी भारतीय भाषाओं के विकास से अलग नहीं है. दरअसल सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य का जोरदार आरंभ आधुनिक सांस्कृतिक राष्ट्रीय नवजागरण की पृष्ठभूमि में होता है जो इतनी सृजनात्मक है कि सभी भारतीय भाषाओं का साहित्य इसके विचार सूत्रों को व्यक्त करने का माध्यम दिखाई देता है. सबसे रोचक तथ्य यह है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध और 20वीं शताब्दी के आरंभिक चार दशकों में उत्तर-दक्षिण में ब्रिटिश साम्राज्यवाद से भारत को मुक्ति दिलाने का साहित्य लिखा जाता है. लोकजागरण का सृजन पूरे भारत में कोलाहल करता सुनाई देता है. बंगला में माइकेल मधुसूदन दत्त, हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र, उर्दू में मौलाना हाली, मराठी में केशवसुत का जो देशभक्तिमय स्वर है वही तमिल में सुब्रह्मण्य भारती, कन्नड़ में श्री कंठय्या, मलयालम में वेण्मणि, तेलुगु में वीरेशलिंगम का है.

कन्नड़ के प्रसिद्ध रचनाकार विनायक कृष्ण गोकाक कहते हैं, "पिछले चार-पांच दशकों का दक्षिण भारतीय भाषाओं का साहित्य जीवन से उपजी नई स्थितियों, प्रवृत्तियों, संघर्षों और मानवीय संवेदना के प्रगाढ़ अनुभवों की संपन्नता का साहित्य है. अब इस

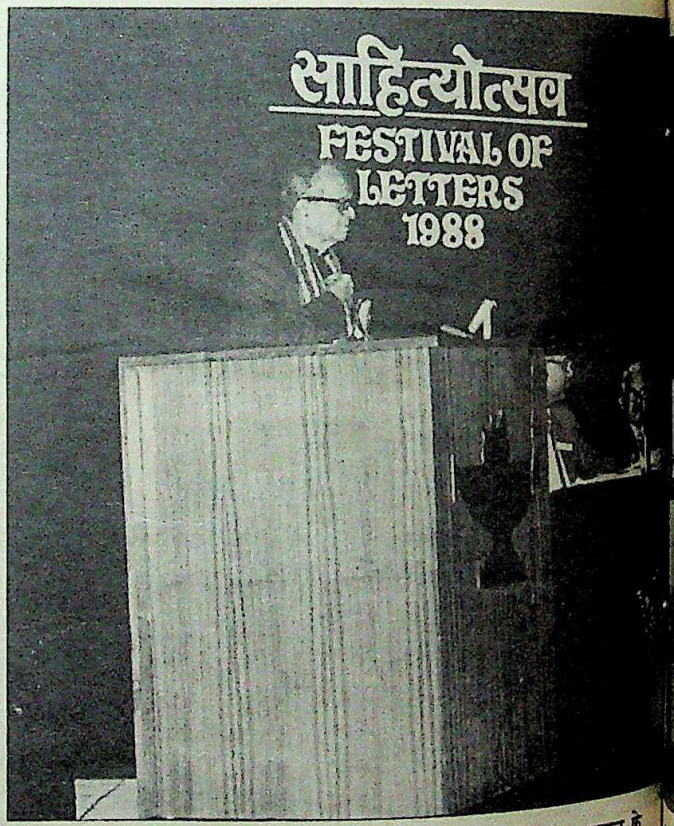

नई दिल्ली में साहित्यकारों का समागमः विचारों के आदान-प्रदान के

साहित्य की अपनी सृजनात्मक मौलिकता और भारतीय देशीयता है." यहां आधुनिक भारतीय भाषाओं के साहित्य का एक ऐसा विराट परिदृश्य सामने आता है जिसमें पूरा देश रीतिवाद के विरोधी स्वर को लेकर जागरण-सुधार युग की क्रांतिकारी चेतना में प्रवेश करता है.

उत्तर को दक्षिण ने और दक्षिण को उत्तर ने साहित्य, कला, संस्कृति, दर्शन आदि के लेन-देन में इतना अधिक प्रभावित किया है कि आर्य-अनार्य का भेदभाव ही मिटता दिखाई देता है. वर्तमान भारत के आर्य, द्रविड़, नाग तथा कोल चारों भाषा परिवार एक दूसरे से गहरे संबद्ध हैं. इसका प्रमाण यह है कि भारत के सभी भाषा परिवारों में वाक्य रचना की लगभग एक-सी पद्धति है. रामायण तथा महाभारत के बिना भारतीय साहित्यिक, सांस्कृतिक अस्मिता की

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कल्पना तक संभव नहीं है. इन काव्यों का विचारतंत्र आर्यवाद, द्रविड़वाद के मूल सांचे को तोड़ता है. वैसे तो भेदभाव का यह सांचा उसी दिन टूट गया था जब दक्षिण का भक्ति आंदोलन उत्तर भारत में कलकल नाद कर उठा था.

दक्षिण भारत की सभी मुख्य भाषाओं का आधुनिक साहित्य प्राचीन भारतीय परंपराओं का नए रचनातंत्र में विस्तार रहा है लेकिन इधर पिछले तीन दशकों में इसके कथ्य और रूपतंत्र में परंपरा और आधुनिकता की रगड़ से नवीन प्रवृत्तियों का गद्य और पद्य में विस्फोट हुआ है. इसमें मनोविश्लेषण शास्त्र, मार्क्सवाद, प्रतीकवाद, अस्तित्ववाद की धमक बढ़ी है. रोमांटिक भावुकता की जगह तर्कपूर्ण और बुद्धिवादी विचारधारा को मिल रही है. आजादी के बाद का मोहभंग उभर रहा है पर इस बात को बेंद्रे, शंकर कुरुप्प, भैरप्पा जैसे रचनाकार बराबर महसूस कर रहे हैं कि एक गहरी सांस्कृतिक उद्भावना की आवश्यकता है जिसकी गति राजधानियों

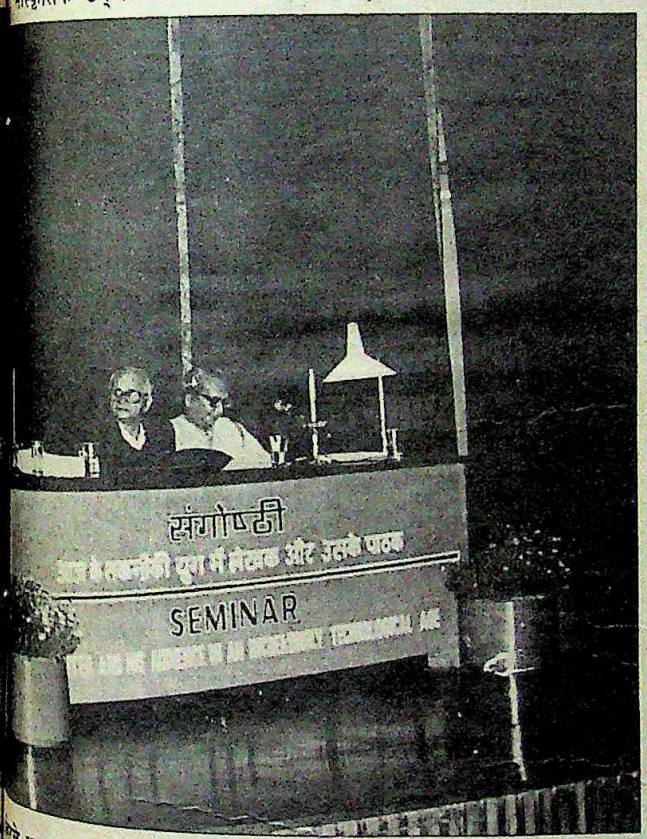

कुछ अवसर

विजय क्रांति

की ओर न होकर गांवों की ओर हो.

तमिल, तेलुगु, मलयालम के समान कन्नड़ का नया सृजन परंपरावाद को छोड़ प्रयोगों की क्रांतिकारी राह ले रहा है. कन्नड़ में पंप, पोन्न, रन्न, नयसेन, अल्लम, बसवेश्वर अक्क, महादेवी, हरिहर, राघवांक, रुद्र, कुमार व्यास, चामरस, पुरंदरदास, कनकदास, तोलम्मा की धर्म-भक्ति परंपरा को तोड़कर नया सृजन उदित हुआ है. देश पर पश्चिमी रोमांटिकों का गहरा असर दिखाई देता है. 20वीं शताब्दी के दो दशकों में अधिकांश अनुवाद रूप में नया सृजन आगे बढ़ा है. इस कार्य में ह. नारायणराव, पंजे मंगेशराव, गोविंद पै, एस.जी. नरसिंहाचारी, बी.एम. श्रीकंठय्या की प्रमुख भूमिका है.

गांधी जी ने जब स्वाधीनता आंदोलन चलाया तो कन्नड़ के सभी कवियों ने नई प्रेरणा, विषय, शैली, छंद की रचनाएं की. मुक्ति, देशप्रेम तथा कन्नड़ भाषाभिमान भी बलवतर हुआ. यह राग श्री. डी.वी. गुडप्पा, मास्ति वेंकटेश आय्यंगर, धारवाड़, बेंद्रे, सालि, आनंदकंद, मंगलूर तिम्मपय्या में प्रबल रूप से विद्यमान है. पश्चिमी रंग की भावगीत धारा कु.वे. पुटप्पा, पुतिन, शंकर भट्ट, विनायक आदि लाते रहे पर कन्नड़ के नए सृजन का उत्तमांश कन्नड़ की समस्याओं-रंगों से जुड़कर ही पनपा है. नए सृजन में शक्ति फूंकने वाले रचनाकार मास्ति श्रीनिवास आय्यंगर हैं. उनकी सृजन पीठिका को रंगनाथ दिवाकर, सालि रामचंद्र राव, बेंद्रे, आनंदकंद, मधुर चन्न, वी. सीतारामय्या, पुटप्पा, नरसिंहाचार्य, राजरत्नम, श्रीकंठय्या, क. शंकर भट्ट, वि.कृ. गोकाक, रसिकरंग, ईश्वर मणकल्ल, सिम्पि लिंगण्णा, के.एस. नरसिंह स्वामी, डी.एस. कर्कि, कृष्णामूर्ति पुराणिक, गोपाल-कृष्ण अडिग, कणवि, शिवरुद्रप्पा जैसे रचनाकार बढ़ाते रहे हैं. कर्कि कहते हैं, "कन्नड़ का समसामयिक सृजन नई भूमिका का ऐतिहासिक दस्तावेज है. इसमें प्रयोग और परंपरा दोनों का आदर है."

उत्तर को दक्षिण ने और दक्षिण को उत्तर ने साहित्य, कला, संस्कृति, आदि के लेन-देन में इतना प्रभावित किया है कि आर्य-अनार्य का भेद मिटता दिखता है. आर्य, द्रविड़, नाग तथा कोल चारों भाषा परिवार आज गहरे संबद्ध हैं

गल्प-उपन्यास में मास्ति श्रीनिवास आय्यंगर अग्रगण्य हैं. वेंकटरामय्या, गोपाल कृष्णराव, रामस्वामी आय्यंगर गांव और शहर पर दृष्टि डालकर नए रूपतंत्र को इजाद कर रहे हैं. गरीबी, अन्याय और आक्रमण के वास्तविक चित्रण में इनकी लेखनी जूझ रही है. बेंद्रे, कुवेंपु, पुतिन, हॉयसल ने कथा-रचना को नया जीवन दर्शन दिया है, तकनीक भी. इधर ईश्वरन, हित्तलमनि, हुयिलगोल, वि.मा. कुलकर्णी, अश्वत्थ, व.मु. जोशी, व्यासराय जैसी नवीन प्रतिभाओं ने जीवन के सूक्ष्म चित्र आंक दिए हैं. कथा-कहानियों के सैकड़ों संग्रह निकल रहे हैं. कन्नड़ की कथा लेखिकाओं में गोरम्मा, श्यामला देवी देवांगना, जयलक्ष्मी, राजलक्ष्मी, गीतादेवी चर्चित नाम हैं. कारंत के उपन्यासों ने, जिनकी संख्या बीस से ऊपर है, वर्तमान समाज का आंखों देखा हाल लिखा है. कृष्णराव, त.रा. सुब्बाराव, कट्टिमनि, कृष्णामूर्ति पुराणिक, अण्णाराव, सीतारामय्या सामाजिक-राजनैतिक उपन्यासों के क्षेत्र के प्रसिद्ध नाम हैं. शंकर भट्ट का 'धूमकेतु', मास्ति का 'चिकवीर राजेंद्र' तथा 'चन्नबसवनायक', के.वी. अय्यर का 'शांतला' जैसे उपन्यास इस कला की उज्जवलता के मानदंड बन गए हैं. उपन्यास के साथ नाटक और रंगमंच कन्नड़ की समृद्ध परंपरा के अंग हैं. नए नाटककारों में टी.पी. कैलासम, आद्यरंगाचार्य, कारंत, कुवेंपु, वेंकटरामय्या ने नए से नए नाट्य प्रयोग किए हैं और नाटक तथा रंगमंच की एक नई दुनिया उपस्थित कर दी है. निबंध कला में मूर्तिराव, गोकाक, बेंद्रे, वाडायिकी आदि नामों की आजकल जैसे धूम मची हुई है.

तमिल साहित्य का आधुनिक काल रामलिंगर, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लै, गोपाल कृष्ण भारती के सृजन से नई करवट पाता है. आधुनिक भारतीय नवजागरण के भीतर से सुब्रह्मण्य भारती, भारतीदासन, कविनायकम पिल्लै जैसे महान रचनाकार उभरते हैं. नामक्कल

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रामलिंगम पिल्लै, कंबदासन, श्रीकृष्ण पिल्लै, सुंदरम पिल्लै तमिल सृजन को लोकभावभूमि पर उतार देते हैं. वी.के. सूर्यनारायण, नरेश अय्यर, एस.के. पार्थसारथी तमिल नाट्य परंपरा का नया रंग निखारते हैं. उपन्यास-कहानी में राजम अय्यर, नरेश शास्त्री, रंगराजू, आर.के. नारायणन, श्रीदेवन, श्रीकल्कि, व्यंकट-रमनि, लक्ष्मी, गुहप्रिया के आने से प्रयोगधर्मी क्रांति जन्मी है.

पहले तो तमिल ने विश्व साहित्य की प्रसिद्ध कहानियों को अनुवादों से और फिर नई कहानी परंपरा को मौलिक रूपतंत्र से जन्म दिया है. वी.वी. अय्यर, वेंकटमनि, राजगोपालन, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, अखिलन, रा. कृष्णमूर्ति, देवन, जगन्नाथन, सरस्वती अम्माड ने जिस कहानी परंपरा को जन्म दिया है वह निरंतर विकसित हो रही है. तमिल कहानी की मनो-विश्लेषणात्मक शैली भारतीय कहानियों के लिए प्रकाश स्तंभ है. वहां रा. कृष्णमूर्ति और रंगनाथन जैसे मनोवैज्ञानिक कहानीकार हैं और कल्कि जैसे हास्य-व्यंग्य निपुण कहानीकार भी. वी.एस. रामय्या जैसे लोकभूमि के कहानीकार हैं और देवन जैसे मनोरंजन शैली के कहानीकार भी. टी.एन. सुब्रह्मण्यम, नाडोडि, ए.एस.वी. अय्यर, व.रा. जैसे कहानीकार कहानी कला का स्वयं एक इतिहास हैं.

कन्नड़ के समसामयिक सृजन में प्रयोग और परंपरा दोनों का आदर है. रचना को नया जीवन दर्शन मिला है. उधर तमिल साहित्य किसी परंपरा का पिछलग्गू नहीं. नए प्रयोग हो रहे हैं, पश्चिम की नकल नहीं

साहित्य अकादमी

कन्नड़ साहित्यकार वि.कृ. गोकाक: नया सृजन

विजय क्रांति

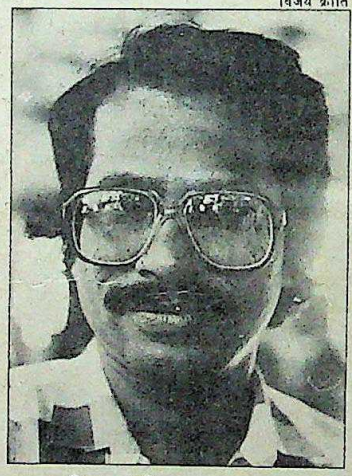

तमिल कवि ए. राजाराव: युवा स्वर

पिछले तीन-चार दशकों में तमिल में आलोचना साहित्य का बहुमुखी विकास हुआ है. इसके उन्नायकों में सुब्रह्मण्य अय्यर, रा. राधक्ययंगर, पी. आचार्य, सेतु पिल्लै, सोमसुंदर भारतीय, गोपाल कृष्णामाचार्य, लो.मु. भास्कर, श्रीनिवास राघवन, तोंडैमान, मीनाक्षीसुंदरम पिल्लै प्रमुख हैं. कल्याणसुंदरम, मुदलियार, मरैमलै अडिगड जैसे आलोचकों का नया चिंतन भी भारतीय समीक्षा को नई देन है. श्रीसंतानम, शिवेरामन, अविनाशलिंगम, वेंकटाचारी निबंधों की नई दिशा खोज रहे हैं पर यह क्षेत्र अभी वहां काफी कमजोर दिखाई देता है.

तमिल साहित्य आत्मकथा, लोक साहित्य, संस्मरण, यात्रा साहित्य की ओर इन्हीं दशकों में बढ़ा है. खोजपूर्ण साहित्य, इतिहास, अनुवाद, धर्मशास्त्र के साथ नया तमिल साहित्य यात्रा और संस्मरण की ओर गतिशील है. खोजपूर्ण साहित्य के क्षेत्र में स्वामीनाथ अय्यर, दामोदरम, सोमसुंदरम भारती आगे बढ़े हैं. तमिल भाषा और साहित्य पर कार्य के लिए प्रो. नीलकंठ शास्त्री, पूर्णलिंगम पिल्लै, राम-चंद्र दीक्षित के नाम आज भी स्मरणीय हैं. तमिल के अनुवादक प्राचीन काल में संस्कृत साहित्य को अपनी भाषा में लाते रहे हैं पर अब यह कार्य और जोर पकड़ गया है. तमिल का नया सृजन कितनी गति से चल रहा है इसका जीवित प्रमाण है पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन. भारती की 'इंदिया' की परंपरा को चितामणि, नवशक्ति, मणिक्कोडि, मंजरी, कुमुदम, चंदामामा, कलैमगंठ जैसी पत्र-पत्रिकाएं आगे किए हुए हैं. तमिल के युवा कवि ए. राजाराव (ब्रह्मराजन) से जब तीन-चार दशक के तमिल साहित्य की प्रगति पर बात हुई तो उन्होंने कहा, "तमिल साहित्य किसी भी परंपरा का पिछलग्गू नहीं है. उसने हमेशा नई क्रांतिकारी दृष्टि को अपने परिवेश से विकसित किया है. कविता, कहानी, उपन्यास में नए-से-नए प्रयोग हो रहे हैं. पर इनमें पश्चिम की नकल नहीं है. हमारा नया साहित्य मानव-द्रोही राजनीति के खिलाफ संघर्ष कर रहा है, करता रहा है."

तेलुगु के पास प्राचीन साहित्य की एक मूल्यवान परंपरा है. यह परंपरा शक्ति के रूप में इधर के समसामयिक साहित्य को गतिवान बनाए हुए है. आर्य, द्रविड़ दोनों संस्कृतियों का बहुत कुछ ग्रहण करने के कारण तेलुगु साहित्य पर संस्कृत तथा तमिल दोनों का काफी असर है. नन्नय भट्ट, नारायण, भास्कर, गोरन्न, पोतन्ना, तिम्मन्न, अप्प, कृष्णमूर्ति शास्त्री, पिंडिप्रोलु लक्ष्मण की साहित्यिक परंपरा तेलुगु में वीरेश-लिंगम के आने पर क्रांति-कारी मोड़ लेती है.

तेलुगु में अंग्रेजी संपर्क से 'रोमांस' का प्रवेश हुआ पर शीघ्र ही बंगला साहित्य के प्रभाव से नवीन दिशाएं खुलने लगीं. 1920 के बाद तेलुगु साहित्य राष्ट्रीय मुक्ति भावना के गीतों से भर गया. 1930 के पास मार्क्सवादी विचारधारा का तेलुगु पर प्रभाव पड़ा और तेलुगु प्रगतिवाद सामने आया. इधर बड्डादि सुब्बाराव; जयंति रामय्या, श्रीपाद कृष्णमूर्ति, शेषाद्रि शर्मा, वेलूरी शिवराम शास्त्री, विश्वनाथ सत्यनारायण, रामप्रोलु सुब्बाराव जैसों का स्वच्छंदतावादी काव्य समृद्धि का एहसास कराता है. 1940 के बाद प्रगतिवादी काव्य में श्रीरंगम श्रीनिवासराव, श्रीदाशरथि उदित हुए.

नई काव्य धारा में पापय्य शास्त्री, नरसय्य चौधुरी, गुरुजाड, राघवराव, तिलक, श्रीराम शास्त्री, विश्वम निखिलेश्वर, रामुलु रेड्डी, नारायण रेड्डी और दाशरथि के नाम उल्लेखनीय हैं. विश्वम का काव्य 'पेन्निटियाट' ग्रामीण जीवन की व्यथा का सृजन है. नारायण रेड्डी 'नागार्जुन सागर' तथा 'गेयकाव्य' जैसी कृतियों में तेलुगु जनता के जीवन रंग बिंबों, प्रतीकों में रचते हैं; दाशरथि 'महाघ्रोदयम', जैसे काव्य संग्रह में आक्रोश, विषमता-विडंबना का स्वर अपनाते हैं. पर तेलुगु काव्य अस्तित्ववादी विचारधारा की गिरफ्त से पूरी तरह मुक्त है. उसकी नई बिंब-प्रतीक-लय शैली

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

हमने स्वप्न सजाये

कर्ल-ऑन बनाते समय हमारे दिमाग में सबसे प्रथम बात थी, आपके सोने के आराम की, शरीर के सहारे की, और आलीशान शान की, इन तीनों के मिश्रण के कमाल के कारण ही तो कर्ल-ऑन गद्दे भारत में सबसे ज्यादा बिकते हैं।

आराम, सहारे, और शान के लिए

Kurl-on®

भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले गद्दे।

कर्नाटक कंज्यूमर प्रॉडक्टस लिमिटेड

मार्केटिंग डिविज़न: इंडस्ट्री हाउस, 45 फेयर फील्ड रोड, बेंगलूर 560 001. फोन: 72710.

क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय: बेंगलूर फोन: 76746, 220314 एवं 224676; कोचीन फोन: 366744; मद्रास फोन: 831710; हैदराबाद फोन: 234560; कलकत्ता फोन: 282089; बम्बई फोन: 5113220 अहमदाबाद फोन: 462601; दिल्ली फोन: 772019 एवं 732133; गुवाहाटी फोन: 23612 (पीपी); राउरकेला फोन: 2535 (पीपी); होसूर फोन: 6992

कार्यालय पटना, भुवनेश्वर, फरीदाबाद, गाजियाबाद, सारोला और भोपाल में भी है।

MASS/KURLON/88

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सोने पे सुहागा–गोल्ड का सदाबहार हरा

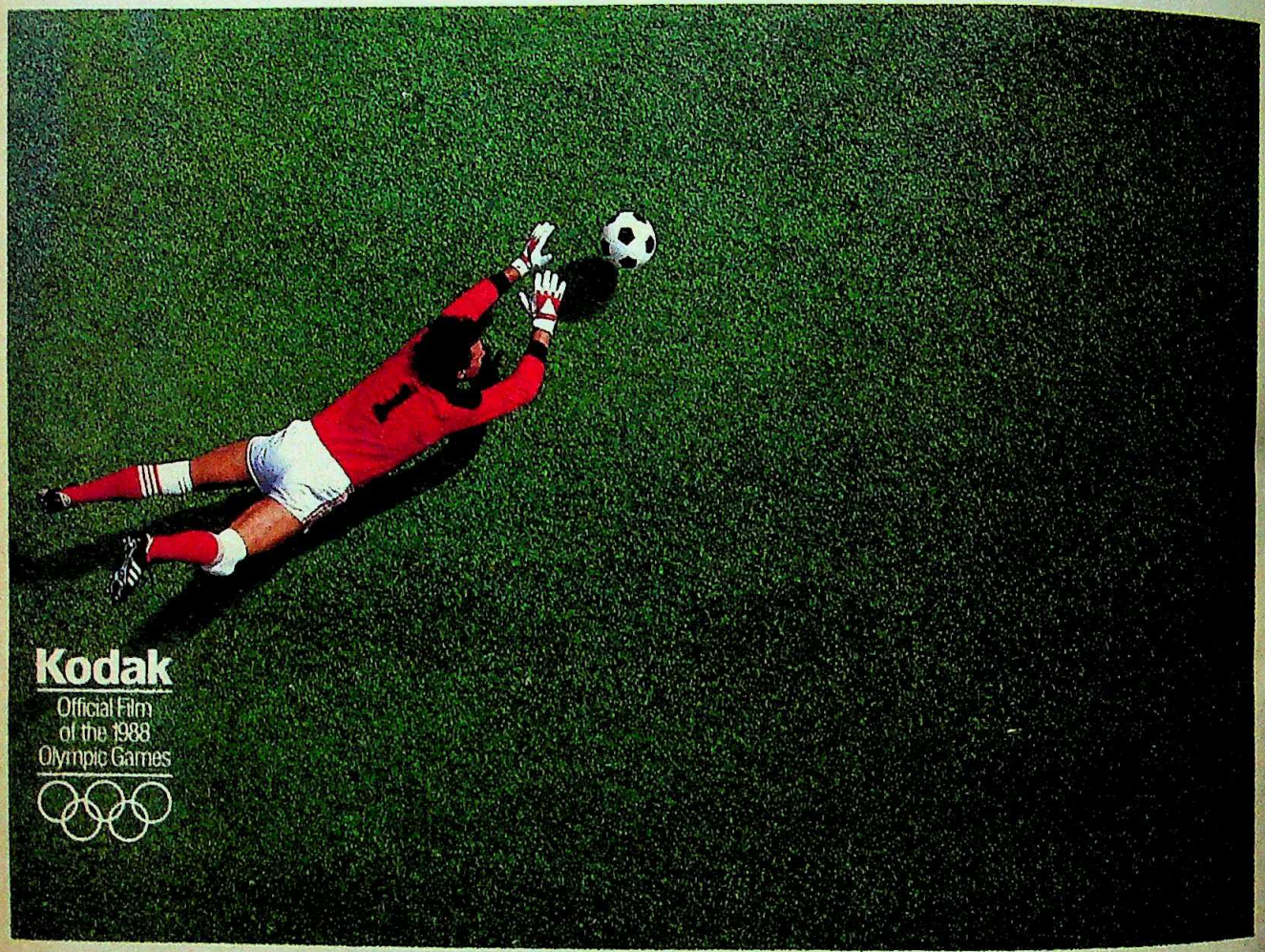

कोडाकलर गोल्ड

चमकीला नीला, सदाबहार हरा, जगमगाता पीला, सुर्ख़ लाल. कोडाकलर गोल्ड फ़िल्म हो तो जीवन का हर रंग खिल उठे बेहतरीन, बेमिसाल. उन्नत तकनीक के फलस्वरूप रंग ऐसे निखर आयें कि हर चित्र सजीव हो जाये.

एकमात्र कोडक की तकनीक का कमाल–कोडाकलर गोल्ड फ़िल्म.

लोग जानते हैं इसका मोल– तभी इसका नाम रखा है–गोल्ड.

Kodak is colour

HTA 1901

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इटेलियन राज़ की बात.
रीजेंसी.
कारोबारी दुनिया में सनसनी
फैलाती एक गरमागरम खबर.

REGENCY
ITALIAN
CERAMIC TILES

आजकल गठबंधनों का ज़माना है और सबसे सनसनीखेज़ गठबंधन है रीजेंसी का, जी हां! रीजेंसी याने खूबसूरती और मज़बूती के साथ शानो-शौकत का गठबंधन... इटेलियन शानो-शौकत का. अब जबकि रीजेंसी है आपके पास, तो फिर सीलनभरे गलीचों को कह दिया जाए कि वे कमरे से तशरीफ़ ले जाएं और साथ ही भद्दे, खरोंचभरे, दाग़दार टाइलों को भी लेते जाएं. सच तो ये है कि कारोबार के लिए रीजेंसी से बढ़कर कुछ भी नहीं इसकी मज़बूती बेमिसाल है. इसकी खूबसूरती इसकी व्यावहारिकता को राज़ ही बनाए रखती है. इतनी ही नहीं, दफ़्तर के फ़र्श को बदलना भी कितना आसान हो गया है. रीजेंसी के साथ दिन-दिन भर फ़र्श को रगड़ने-चमकाने की झंझट भी खत्म. आपका फ़र्श चुटकियाँ बजाते ही तैयार... है ना कमाल?
रीजेंसी. स्टाइल वाला टाइल. क्यों न हो, इसे इटली की वेलको इंडस्ट्रीएल के सहयोग से निर्मित किया जाता है, जो कि दुनिया भर में अव्वल नंबर पर है. अब तो बस रीजेंसी लगाइए कारोबार का भविष्य सहसा उजला लगने लगेगा.!

सबसे मज़बूत फ़र्श अपनाइए सबसे खूबसूरत सबब के लिए

रीजेंसी सिरामिक्स लिमिटेड

राघव रत्न टावर्स, चिराग़ अली लेन, हैदराबाद-५०० ००१. फोन : २३७२६६/२३३०१७. टेलेक्स : ०४२५-६९५३ RCL IN.

Sista's-RCL-237/88 HN A

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Manju ®

घर, खेत एवं कल-कारखानों को उज्जवलित करने वाली - मन्जु

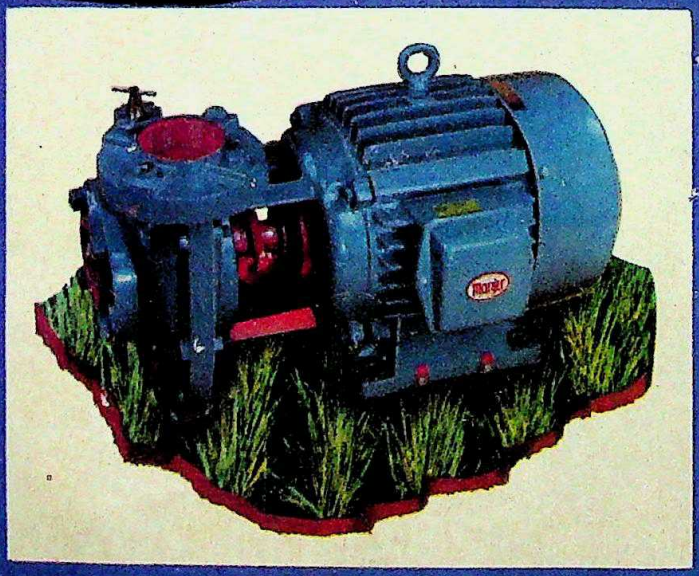

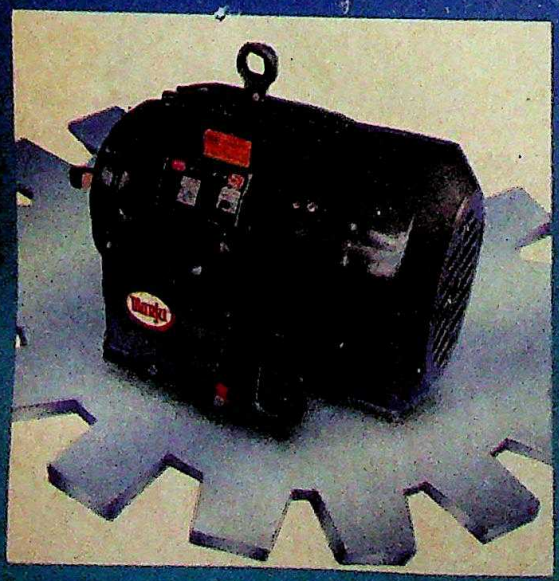

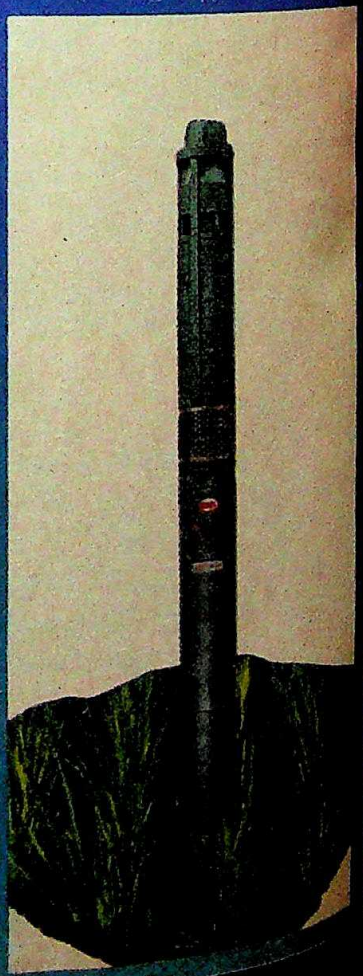

Manju ®

खेती, गृहस्ती एवं उद्योग के लिए मोटर, मोनोब्लाक एवं पंपसेट ।

सर्वोत्तम कोटि
आई- एस- आई प्रमाणन
वाजिब दाम
विस्तृत श्रेणी

Built tough. Built to last.

मन्जु इलेक्ट्रिकल इन्डस्ट्रीज़ लिमिटेड
पोल्लाची रोड़, कोयम्बतूर 641 021

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

चॉकलेट अब एक नए रंग-रूप, नए स्वाद में!

दूधिया सफ़ेद चॉकलेट आज़माइए! स्वादभरा मज़ेदार फ़र्क पाइए. ऐसा लाजवाब स्वाद आपको और कहीं नहीं मिल सकता. कैम्पको व्हाइट क्रीमी चॉकलेट... चखकर देखिए, मान जाएंगे!!

भारत के सबसे बड़े सबसे आधुनिक प्लांट में निर्मित.

Campco

कैम्पको लिमिटेड
मैंगलोर

CC-0 ... Domain. Gu... Wa...

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

समय बदल गया है...

बेहतर के लिए.

बेहतर टेक्नॉलजी. बेहतर स्टाइल.
और बेहतर श्रेणी के लिए.

ऑल्विन
क्वार्ट्ज़

भारत की सबसे ज़्यादा बिकनेवाली
क्वार्ट्ज़ घड़ियाँ

Time
FOR THE NEW GENERATION
ALLWYN

Manufactured under licence from
SEIKO

...ri Collection, Haridwar

R K SWAMY/HAL/SCHEMA

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Long-playing hits from Neycer

Be it Silver Spots or Silver Flake. Fern Green or Green Ripple... their very names roll off like liquid notes.

Neycer Tiles come in 14 exquisite shades and designs that bring harmony to any floor. Made to rigid international standards, Neycer gives you not just tiles ... but classics in clay.

Neycer

Neycer Tiles
Beauty that is classic
Beauty that defies age

Neiveli Ceramics & Refractories Limited 109 Nungambakkam High Road Madras 600 034

OBM 567 A

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जिस घड़ी वह पहले-पहल कैम्प में जाये, उसका मन खुशी से फूले न समाये.

"हसीन एचएमटी!"

hmt
घड़ियां
राष्ट्र के समय प्रहरी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आसपास के अनुभवों से कविता रचती है.

कविता की भांति तेलुगु नाटक की अपनी भूमि है. धूम रही. पर लक्ष्मीकांतम कोप्परयु सुब्बाराव, तिरुपति वेंकटेश्वर जैसों के उदय से नए नाटक की रचना हुई है. कामेश्वरराव 'अन्नी तगादाले', 'अप्पुडु' जैसे हास्य-व्यंग्य रचा है. कामेश्वरराव 'अन्नी तगादाले', 'अप्पुडु' जैसे हास्य-व्यंग्य एकांकी रच रहे हैं. वेंकट राजमन्नार, विश्वनाथ शर्मा, आचार्य आत्रेय, बाला त्रिपुरसुंदरी के प्रयासों से नाटक तथा रंगमंच में नया युग उदित हो रहा है. पिछले तीन चार दशकों का तेलुगु साहित्य पद्य-गद्य की नवीन प्रवृत्तियों का उद्घोषक बन गया है. निखिलेश्वर कहते हैं, "हमारा सृजन नारों-वादों में नहीं, नवीन एहसास में जी रहा है. ज्यादातर नए रचनाकार परंपरा की गहराई में उतरकर उसका नया अर्थ तलाश रहे हैं."

मलयालम साहित्य की सृजन चेतना में प्रकृति, सौंदर्य और चंदन की गंध अधिक रची-बसी मिलती है. संस्कृत, तमिल शब्दों के प्रवाह से यहां 'मणिप्रवाल शैली' विकसित हुई. एक मत यह भी है कि संस्कृत तथा मलयालम का मिश्रण ही मणिप्रवाल शैली है और यह 'लीलानिलकम' में रूप पाकर निखरती है. नाटन पाट्टुकल (लोक-गीत) की परंपरा से यह साहित्य भरा पड़ा है. चंपूकाव्य, मुक्तक, भक्ति-दर्शन के गीत, कथकलि साहित्य की धाराएं इसमें अरसे से प्रवाहित हैं. चेरुश्शोरी, रामनुजम, कुंचन नंपियार का प्रभाव आधुनिक युग के सृजन पर छाप छोड़ता मिलता है.

विजय क्रांति

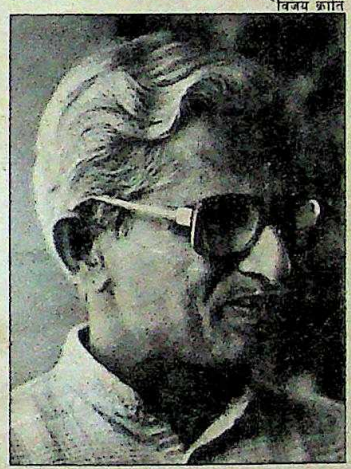

तेलुगु कवि निखिलेश्वरः नए एहसास

विजय क्रांति

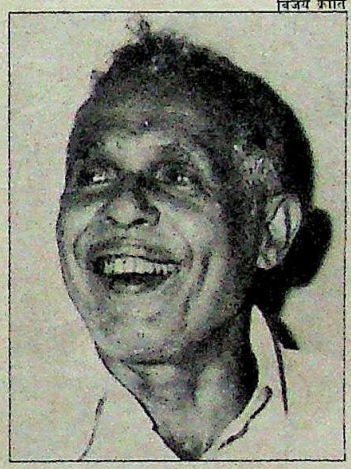

मलयालम लेखक तकषी एस. पिल्लैः दायित्व का बोध

केरल के वर्तमान काव्य साहित्य पर कुमारणआशान, उल्लूर, केशव पिल्लै तथा वल्लतौल की गहरी सृजन-धमक है. इसी धारा को सुब्रह्मण्यम पोट्टी, बालकृष्ण पणिक्कर, मेनवन, के.एम. पणिक्कर, जी. शंकर कुरुप्प, कृष्णा पिल्लै, राजराज वर्मा, नंपूतिरी जैसे कवि विस्तार देते हैं. इसी धारा को राघवन पिल्लै, चंगडंपुषा कृष्ण पिल्लै के क्रांति गीतों से गहराई मिलती है. प्रगतिवादी आधार में सामाजिक क्रांति करने का स्वर पय्यक्कुट्टि जैसे कवि में प्रमुख है. इधर के दशकों में एम.पी. अप्पन, नालांकाल कृष्ण पिल्लै, श्रीधर मेनन, एन.पी. कृष्ण वारियर, गोविंदन नायर, वयलार रामवर्मा, ओ.एन.वी. कुरुप्प, अविक्कम् ओलप्पमण्णा, ओ.एम. अनुजन, जी. कुमार पिल्लै, चंद्रशेखरन नायर, माधवन पिल्लै, कुमार नायर, ईश्वर वारियर जैसे कवियों का भारी समूह दृष्टिगत होता है.

उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना तथा दूसरी गद्य विधाओं में मलयालम का नया साहित्य अंग्रेजी से अभिभूत दिखाई देता है. उपन्यास की मंद धारा को के.एम. पणिक्कर 'केरलसिंह', 'धूमकेतु का उदय', 'परंकि पटयाली' जैसे उपन्यास लिखकर गति देते हैं. चंतुमेनन की धारा को सी.वी. का 'प्रेमामृत' उपन्यास नया रूपतंत्र देता है. पर केशवदेव तथा तकषी शिवशंकर पिल्लै के आने से उपन्यास, कहानी में नया युग आ जाता है. तकषी ने मोपासां की यथार्थवादी शैली के अनुकरण पर पहले पहल पतित पंकजम, प्रतिफलम् जैसे उपन्यास लिखे हैं. इनमें नैतिकता तथा सदाचार की परंपरागत मान्यताओं का सीधा विरोध किया गया है—फलतः कट्टरपंथियों ने इनका जोरदार विरोध किया. पर तकषी रुके नहीं. वे कहते हैं, "उपन्यास एक सड़ी-गली व्यवस्था के विरोध में उठे हुए हाथ हैं. मैं साधारण आदमी की हिम्मत बढ़ाने में विश्वास रखता हूं तथा सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करते हुए उन्हें बदलना चाहता हूं. फिर मैं वही लिखता हूं जो मेरा खूब जाना-पहचाना होता है. वास्तविकता के अनुमान भर से मैं कलम नहीं उठाता. रचनाकर्म बड़े दायित्व का कर्म है—यह समझकर ही मैं लिखता हूं."

तकषी के साथ श्री बशीर 'बाल्यकाल सखी', पोट्टेक्काट्ट 'विषकन्यका', जोसेफ मुंडश्शोरी 'कोन्तयुम कुरिशु' जैसे यथार्थवादी उपन्यास लिखते रहे हैं. कहानी के क्षेत्र में पी.सी. कुट्टीकृष्णन, पोनकुन्नम् वर्की, के.टी. मुहम्मद, पोट्टीक्काट्ट बशीर, कोवूर, कारूर, नीलकंठ पिल्लै, चेल्लपन नायर, ललितांबिका, सरस्वती अम्मा ने दलितों-शोषितों, श्रमिकों पर कहानियां लिखकर नया विचार क्षेत्र दिया है. कहानी कला के साथ नाटक और रंगमंच के क्षेत्र में 'कथकलि कला' का विस्तार होता है. के.एम. पणिक्कर, सी.वी. रमन, ई.वी. कृष्ण पिल्लै, कैनिक्करा पद्मनाभ पिल्लै, इडामेरी गोविंदम नाटक और अभिनय दोनों में अग्रणी रहे हैं. पणिक्कर ने 'मंदोदरी', 'भीष्मर', रमन पिल्लै ने 'कुरुपिल्ला कलरि', कृष्ण पिल्लै ने 'सीता', पद्मनाभ पिल्लै ने 'कालिवालिले कल्पपादप' जैसे श्रेष्ठ नाटक लिखे हैं. कई नाटककारों ने लोकनाट्य परंपरा को पुनर्जीवित किया है. विश्व तथा भारतीय भाषाओं के श्रेष्ठ ग्रंथों के अनुवाद में मलयालम साहित्य अग्रणी है. जीवनी, साहित्य, रेखा चित्र, रिपोर्ताज को पिछले दो दशकों में यहां विशेष महत्व मिला है.

तेलुगु की प्राचीन साहित्य परंपरा ने नए साहित्य को भी गतिवान बनाए रखा है. नए रचनाकार परंपरा की गहराई में उतर उसका नया अर्थ तलाश रहे हैं. जबकि मलयालम में परंपरागत मान्यताओं का विरोध उजागर हो रहा है

दक्षिण भारतीय भाषाओं के साहित्य के इस अधुनातन पक्ष के दृश्यालेख के आधार पर एक राय निश्चित बनती है कि इन भाषाओं के साहित्य की नवीन प्रवृत्तियों ने एक नवीन सृजनात्मकता, वैचारिकता तथा देशी मौलिकता को ठौर-ठिकाने के साथ विकसित किया है. इन भाषाओं का नवीन सृजन भारतीय सृजनात्मकता के उज्ज्वल रंगों, ध्वनियों, प्रतीकों, बिंबों, अर्थ-लयों का समृद्ध और संभावनापूर्ण संसार है.

—कृष्णदत्त पालीवाल

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

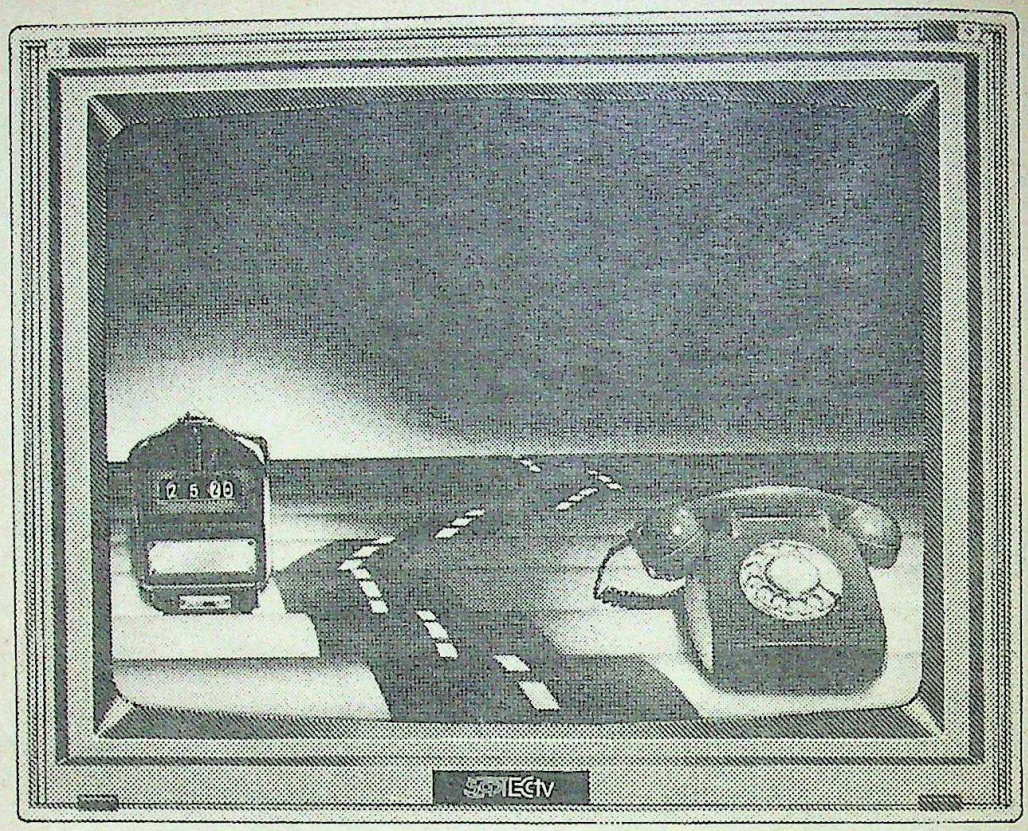

क्या बिक्री-पश्चात सेवा पाने के लिए आप इस हद तक जाएंगे?

या फिर इस हद तक?

जब आप ई सी टी वी खरीदते हैं
तो उससे जुड़ा हमारा वादा भी पाते हैं.
बिक्री-बाद सेवा जब चाहें. बस, हमारा फ़ोन नम्बर घुमाएं.
यानी आपको अपना सेट लेकर भटकना न पड़े दर-दर.
हमारा प्रतिनिधि आपके घर आएगा
वहीं के वहीं सेट ठीक कर जाएगा.
वैसे सेवा की नौबत ही कब आती है
क्योंकि हर ई सी टी वी बरसों चले – ऐसी बुनियाद डाली जाती है.
हर हिस्सा, हर पुर्जा जांचा परखा.
जो दें मनमोहक रंग छटा.
शानदार आवाज़.
और हरदम स्पष्ट और साफ़ चित्र.
साल-दर-साल.

ECtv

यही है वो टीवी जिसकी नकल हर कोई करना चाहता है.

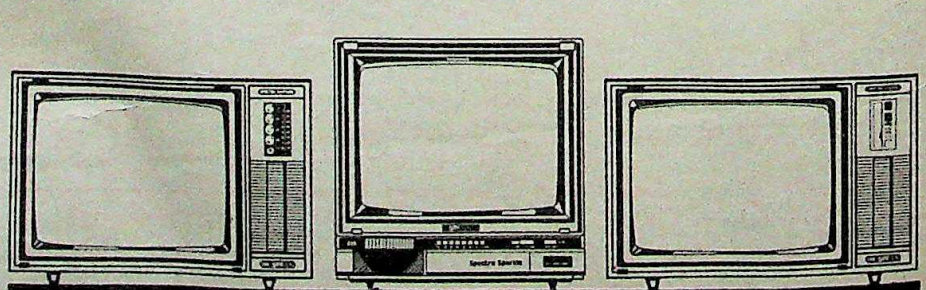

20 YEARS

इकतेक इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का एक उद्यम), हैदराबाद-५०० ७६२.
शोरूम्स: अहमदाबाद फोन : ७६३०४ ●आसनसोल ●बंगलौर फ़ोन : २५८६२०, २८१९२, ७०६४९ ●बम्बई फ़ोन : ४३०००३४, ४३०२७३४ ●थाणे फ़ोन : ५९४५३९ ●कलकत्ता फ़ोन : ४५९६६९, ४५९३५७ ●चंडीगढ़ फ़ोन : ३१११३ ●कोचीन ●धनबाद ●हैदराबाद फ़ोन : २३२६८५, २३३२४८ ●इंदौर फ़ोन : ३६६९५ ●जयपुर फ़ोन : ६९६०४ ●कानपुर फ़ोन : २४८१६९ ●लखनऊ फ़ोन ४२६८३, ४५९०६ ●मद्रास फ़ोन : ४५१७२१, ४५०७४९, ४५२२९६, ४५२३३९ ●नागपुर फ़ोन : ४५७५६ ●नई दिल्ली फ़ोन : ५२७३६०, ५२६०५५, ७७१०५०, ७७१३१९ ●पानीपत ●पूणे फ़ोन ३२५८८, ३३०६२ ●रायपुर फ़ोन : २४७७२ ●तिरुपति फ़ोन : ५३१३ ● विजयवाडा फ़ोन : ६४६२९ ● विशाखापटनम्

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Karishma/EC/11/2417 HI

Artig/EIDC/006/88

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Tamilnadu — a rich heritage of culture and industrial growth.

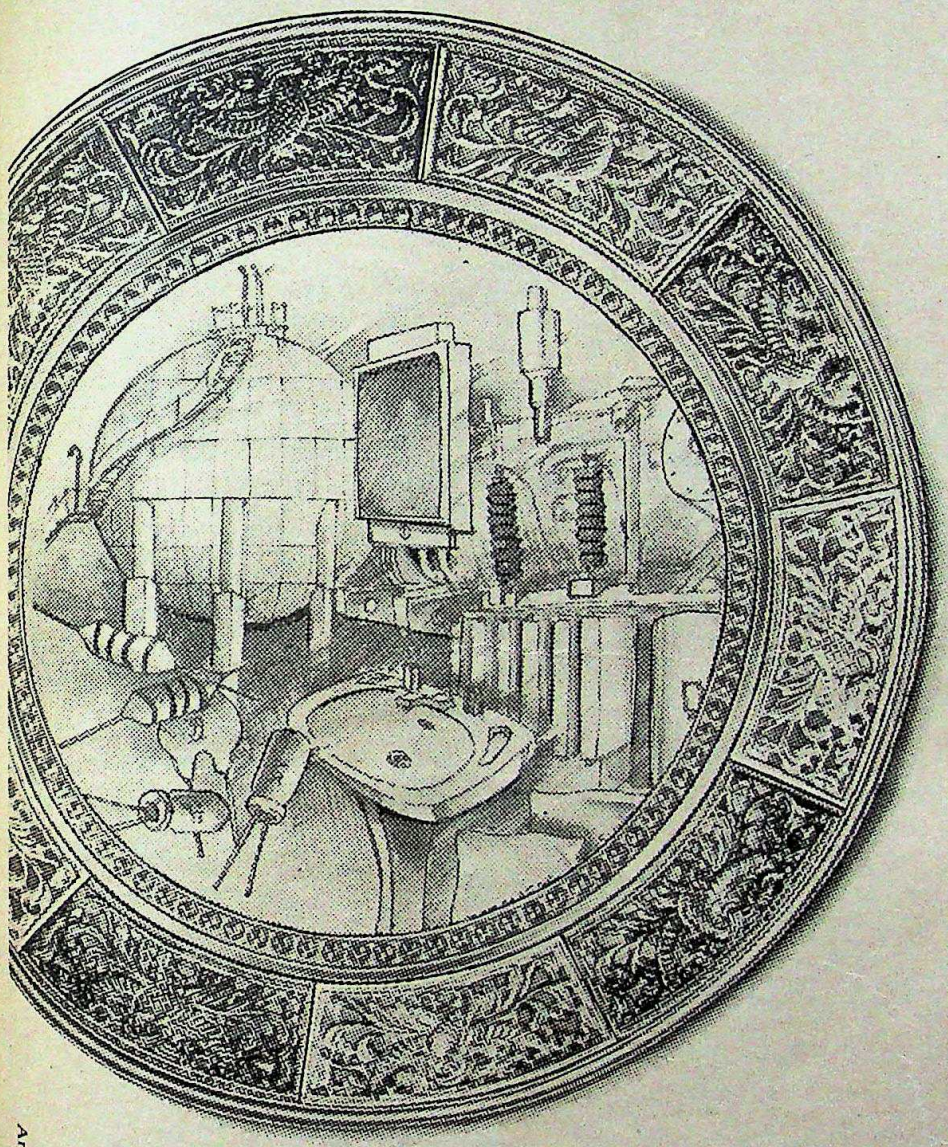

Artig/EIDC/006/88

Parrys — a pioneering participant for 2 centuries.

Tamilnadu — a land of tradition and culture has not lost sight of its traditional cottage ventures of arts and crafts. Yet today it is recognised as a powerful industrial state, with a wide range of manufacturing activities.

In two centuries Parrys has also grown from trading to more modern activities; sugar, fertilizer, confectionery, ceramics, marketing of consumer and engineering goods, shipping and travel.

Today, Parrys is working towards increased productivity, growth and a dynamic future.

PARRYS

Estd. 1788

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आज,आप अपनी पत्नी को ज़िन्दगी में कई चीज़ों की चिन्ताओं से मुक्त रख सकते हैं।

आपकी पत्नी के लिए उसका घर ही उसकी दुनिया है। दिन रात काम करके वह उसे आपके लिए सजाती संवारती है.... घर की छोटी से छोटी चीज़ भी उसके लिए बड़ा महत्त्व रखती है। इतनी मेहनत और सावधानी से जुटायी गई गृहस्थी की सुरक्षा के लिए उसकी आंखें हमेशा आपकी ओर लगी रहती हैं क्योंकि आप ही उस के सुरक्षा प्रतीक हैं।

एक कार्य करके आप उसे हज़ार चिन्ताओं से मुक्त रख सकते हैं, "उसकी दुनिया सुरक्षित है"— बता सकते हैं।

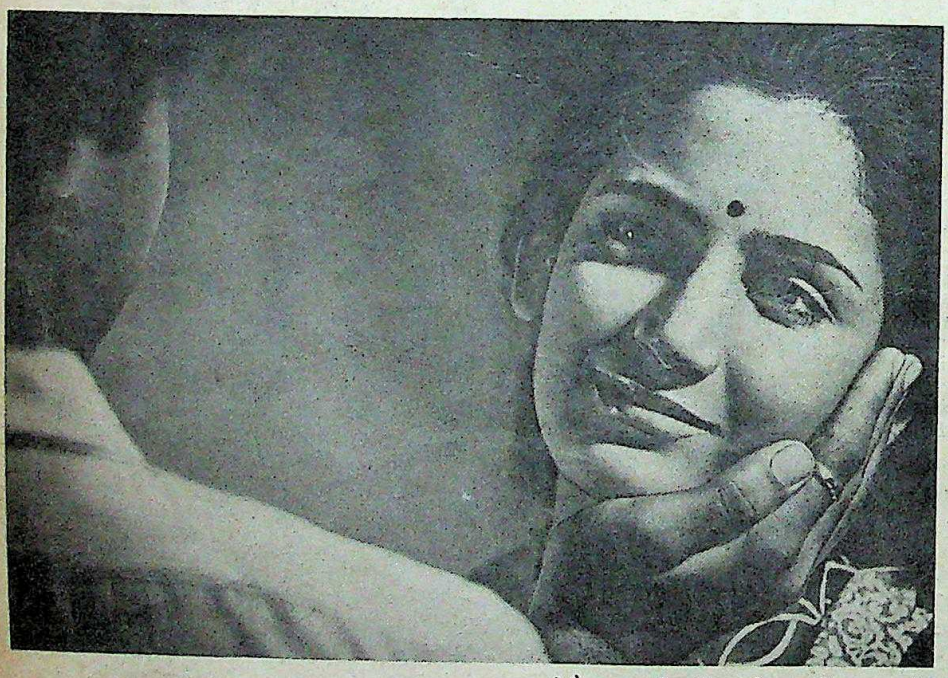

युनाइटेड इण्डिया की हाउसहोल्डर्स बीमा पॉलिसी— वो एक कार्य जो हज़ार भावनाओं के बराबर है।

हर समय घर में ताला लगाते समय हर नारी के मन में यही डर समाया रहता है कि हर चीज़ सुरक्षित रहेगी या नहीं। भला ऐसे डर की क्या ज़रूरत है?

युनाइटेड इण्डिया की हाउसहोल्डर्स बीमा पॉलिसी आपके घर को ऐसी सुरक्षा दे जो किसी ताले से नहीं मिल सकती। यह पॉलिसी आपके घर की चीज़ों को केवल चोरी के प्रति ही सुरक्षा नहीं देती बल्कि आग, बाढ़ व अन्य जोखिमों के प्रति भी सुरक्षा प्रदान करती है। आपके ज़ेवर-जवाहारात, टी.वी., साइकिल और अन्य घरेलू उपकरणों का भी बीमा करवाया जा सकता है। इसमें घर के स्थायी निवासियों को भी दुर्घटना के प्रति सुरक्षा दी जाती है..इतना ही नहीं, इसके अंतर्गत अन्य जोखिमों के प्रति भी सुरक्षा शामिल है। जी हां, सिर्फ़ एक कार्य क‹के आप सभी चिन्ताओं से मुक्ति पा सकते हैं।

युनाइटेड इण्डिया में हम,लोगों और उनकी ज़रूरतों को सही तौर पर समझते हैं। आप उद्योगपति हों या भूमिहीन मज़दूर, फैक्टरी में काम करने वाले हों या मुर्गी-पालक कृषक, जहाज़ों के मालिक हों या ताड़ी खींचने वाले— हम तो देशभर में बिखरे अपने ९१५ शाखाओं के द्वारा सभी के पास पहुंचना चाहते हैं। उनकी विशेष ज़रूरतों के अनुसार पॉलिसियां बनाना चाहते हैं और उनके दावों को जल्दी से जल्दी निपटाना चाहते हैं।

जी हां, जब तक जोखिम है,हम आपके साथ हैं,क्योंकि हम हैं— युनाइटेड इण्डिया।

युनाइटेड इण्डिया इन्श्यूरेंस कम्पनी लिमिटेड
(भारतीय साधारण बीमा योजना निगम की एक सहायक कम्पनी)
२४ व्हाइट्स रोड, मद्रास-६०० ०१४

हरदिन,हर पल हम आपके साथ रहेंगे।

Mudra : M : UI : 3523 Hin

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"These are the monuments of real kings ... fathers of their people. These are the grand sepulchres built by the ambition of unsatiable benevolence ... which, not contented with the dispensation of happiness during the contracted term of human life, had strained ... to extend the dominion of their bounty beyond the limits of nature, and to perpetuate themselves through generations of generations ... the nourishers of mankind."

Edmund Burke, 1785
– on the water reservoirs built by the kings of Karnataka

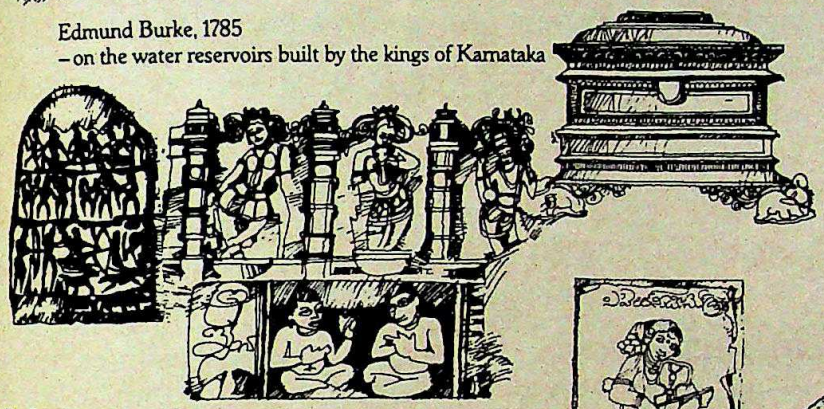

In harmony with eternity

Karnataka. Land of tremendous scenic beauty. Its history a richly-patterned mosaic of kings and their kingdoms. Embellished by an incredible soaring of the creative spirit — in art, music and literature. But it is the remarkable temperament of her rulers that makes Karnataka unique. Embodied in a trinity of sacred traditions carried down through the ages — religious tolerance, patronage of the arts and social welfare.

Sanctuary for the soul

Sarva dharma samanvaya — this sums up the spirit of religious tolerance in Karnataka. Clearly borne out by the Hoysala temple in Belur where Buddha, Jina and Shiva are invoked in the same breath. With the advent of Christianity and Islam, churches and mosques too became important part of community life. The three great saint savants of Hinduism — Ramanujacharya, Sankaracharya and Madhvacharya lived and taught here. So, in Karnataka, religious harmony was and is, a way of life.

Zenith of creation

Art and architecture in Karnataka have evolved to spectacular heights. Witness the innumerable Chalukya and Hoysala temples of Aihole, Badami, Belur and Halebidu. Buddhist stupas. Jain monuments — the giant monolith of Gomateshwara at Shravanabelagola being the finest example. Islamic rule saw the creation of magnificent palaces, mosques and mausoleums. The most famous being the Gol Gumbaz at Bijapur and Tippu Sultan's summer palace.

The outpouring of painting and literature is equally prodigious. And Karnataka has given its name to one of the greatest living traditions of classical music — Carnatic music.

Caring for the common man

The credo of every ruler of Karnataka included a very efficient system of government. Governors and administrators took charge of day-to-day affairs. Cultural and intellectual activities were promoted. Social life followed a strict pattern and all rituals were religiously observed. Peace and harmony reigned and all was well with the world.

Reaching for the stars

From past to present, the people of Karnataka have maintained these traditions. Enlightened and motivated by an unbroken cultural heritage which has imbued them with great maturity of mind and purpose. Little wonder then that the state has front-staged some of the greatest stalwarts of our time — C. V. Raman, Visweswaraya, Seshadri Iyer, Mirza Ismail and many more.

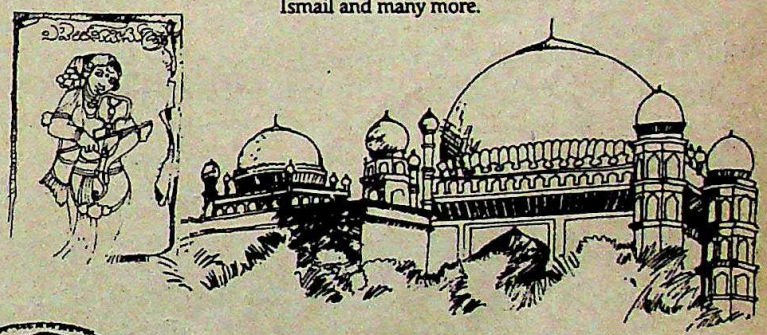

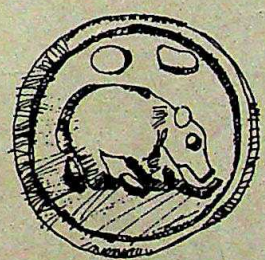

This, then, is Karnataka. A land of glorious traditions and great people. Enriched by a culture exhilarating, enduring and rare. Come, see and experience it for yourself.

karnataka information

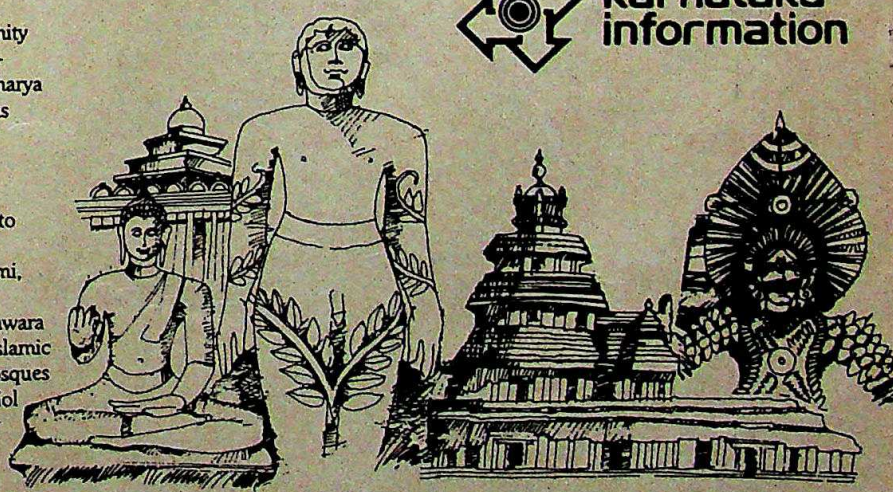

CHAITRA K.DIP-1854-86

Karnataka—a glorious tradition, a great people

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दक्षिण भारत परिशिष्ट

सिनेमा

बदलते दौर के साथ कदमताल

एक दृश्य करीब डेढ़ दशक पहले का: एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ऐसे राज्य में पहुंचता है जहां के राजा ने प्रजा को एक तरह से गुलाम बना रखा है. डॉक्टर यानी हीरो राजा को मारकर जनता को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाता है. लोग न सिर्फ डॉक्टर को अपना राजा स्वीकार कर लेते हैं बल्कि राजा की रूपवती कन्या भी उसे अर्द्धांगिनी के रूप में मिल जाती है. तड़क-भड़क, नाच-गाने और हीरो-हीरोइन के प्रेम प्रसंगों से भरपूर यह तमिल फिल्म थी—'अयिराथिल ओरूवन' (हजारों में एक). इस हिट फिल्म के हीरो थे—तमिलनाडु के दिवंगत मुख्यमंत्री मरुदर गोपाल मेनन रामचंद्रन और हीरोइन थीं—जयललिता.

दूसरा दृश्य 1987 का: हीरो अपराध जगत का एक बड़ा सरगना है जो आम लोगों की मदद करता है. वह न्याय की समानांतर व्यवस्था चलाता है, हत्यारों को यमलोक पहुंचाता है. लोगों को उसके 'दरबार' में इंसाफ तुरत-फुरत मिल जाता है. एक झुग्गी बस्ती गिराने की योजना बनाने वाले एक सेठ के घर को हीरो नेस्तनाबूद कर देता है. गरीब अपने इस हमदर्द को दिलो-जान से चाहते हैं. यह एक कारुणिक

1956 में बनी फिल्म 'तायिन मडियिल्' के सितारे एमजीआर और बी. सरोजा देवी: पारिवारिक ड्रामा

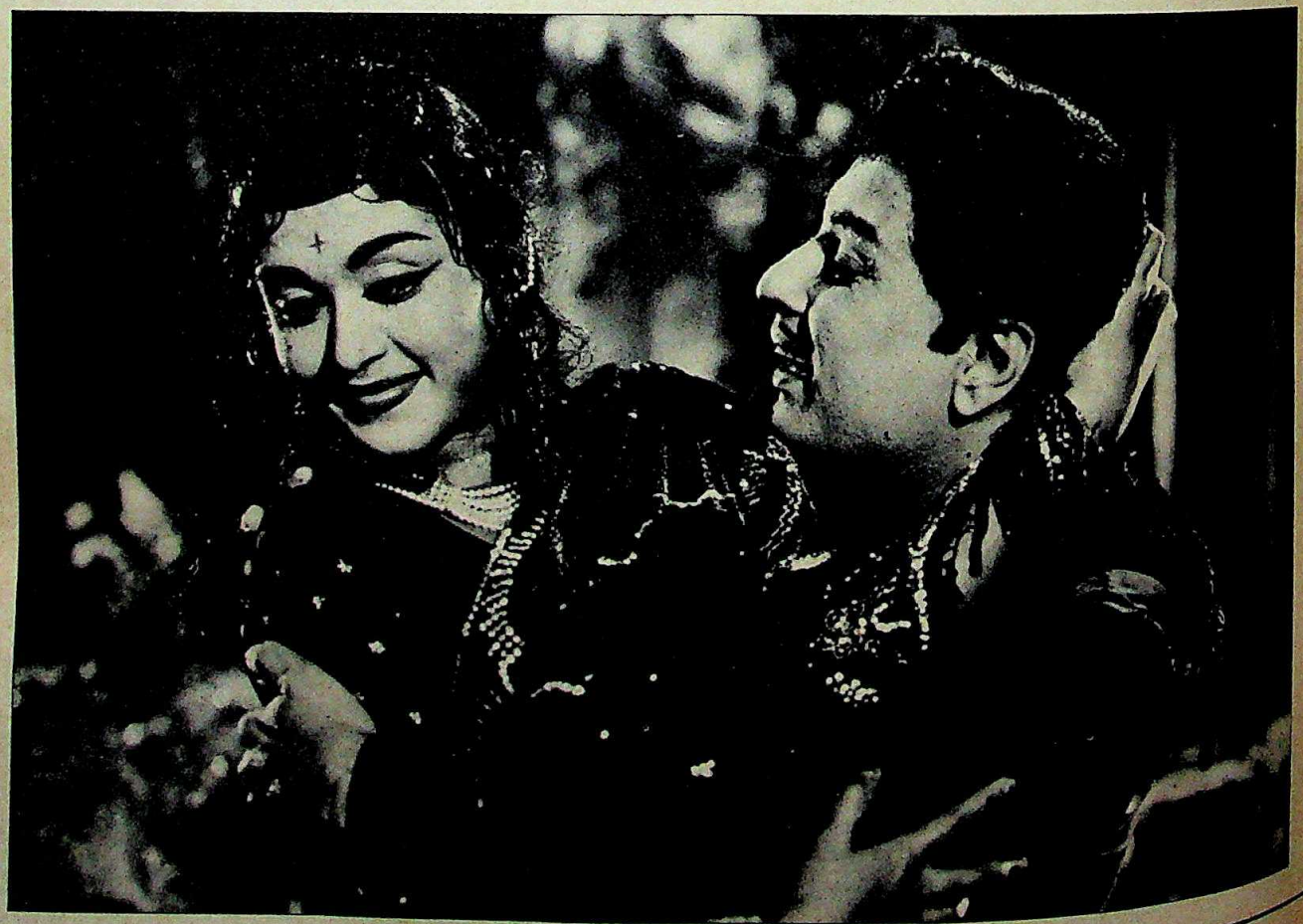

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कहानी है—झकझोर देने वाले विषय और संदेश के साथ. फिल्म अपने मकसद पर खरी उतरती है. इसमें कोई तड़क-भड़क, सजधज, भड़कीले लिबास, रोमांटिक गीत, नाच और चालू प्रेम प्रसंग नहीं है. यह फिल्म है 'नायकन' और इसके नायक हैं—कमल हासन जिन्हें इसमें अभिनय के लिए हाल ही में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है.

'नायकन' तमिल फिल्मों और एक बड़े परिप्रेक्ष्य में पूरे दक्षिण भारतीय सिनेमा में आए बदलाव का एक सटीक प्रतीक है. पिछले दस साल में दक्षिण भारतीय सिनेमा का लगभग कायाकल्प हो गया. फिल्म निर्माण के कई मोर्चों पर दक्षिण का सिनेमा यथार्थ के करीब खिसका है. दर्शकों की रुचि बदलने के साथ-साथ कैमरे को भी अपनी निगाह बदलनी पड़ी है. लेकिन बदलाव अपने साथ कुछ नई और प्रत्याशित समस्याएं भी लाया है. निर्देशन, अभिनय और तकनीक निश्चित रूप से बेहतर हुई है पर फिल्मों का टिकाऊपन खत्म हो रहा है. वितरकों के लिए लाभ की गुंजाइशें सिकुड़ी हैं और निर्माण लागत व डिब्बों में बंद फिल्मों की संख्या निरंतर उठान पर है. प्रेमकथाओं का तो जमाना ही नहीं रहा, अच्छी कहानियां भी कभी-कभार नजर आती हैं. दक्षिण की चारों भाषाओं—तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़—में आज हिंसा, क्रूरता, फार्मूलों और तेजी का बोलबाला है और अनेक पुराने फिल्म निर्माता व कलाकार बदलते दौर से तालमेल बिठाने के लिए जूझ रहे हैं. अपने अस्तित्व की हीरक जयंती के मौके पर दक्षिण भारतीय सिनेमा को एक अप्रत्याशित संक्रमण काल से गुजरना पड़ रहा है.

दक्षिण भारतीय सिनेमा का कायाकल्प हो गया है. निर्देशन, अभिनय और तकनीक सुधरी है पर टिकाऊपन खत्म हो गया है. वितरकों का लाभ घटा है और डिब्बाबंद फिल्मों की संख्या बढ़ी है

1975 में देश भर में 9017 सिनेमाघर थे जिनकी संख्या 1986 में बढ़कर 12,701 हो गई. इनमें से 7476 सिनेमाघर केवल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में हैं. अकेले तमिलनाडु में ही 2700 सिनेमाघर हैं. पिछले साल देश भर में 806 फिल्में सेंसर बोर्ड से पास हुई जिनमें 521 दक्षिण भारतीय भाषाओं की थीं. हिंदी को विशाल दर्शक वर्ग हासिल होने के बावजूद 1987 में सेंसर से हिंदी की जहां 150 फिल्में पास हुईं वहीं तमिल फिल्मों की यह संख्या 167 (देश में सबसे ज्यादा) थी. इसी साल तेलुगु की 163 फिल्मों को प्रमाणपत्र मिला, मलयालम की 103 फिल्में रिलीज हुईं और कन्नड़ की 88 फिल्मों को सेंसर ने हरी झंडी दिखाई—इस तरह समूचे देश में निर्मित होने वाली फिल्मों में दक्षिण भारत का योगदान 70 फीसदी बैठता है. लेकिन ये आंकड़े उन समस्याओं को नहीं बताते जिनसे दक्षिण

1988 की फिल्म 'अग्नि नक्षत्रम्' में प्रभु (बाएं) और कार्तिक (दाएं): हिंसा से लबरेज

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

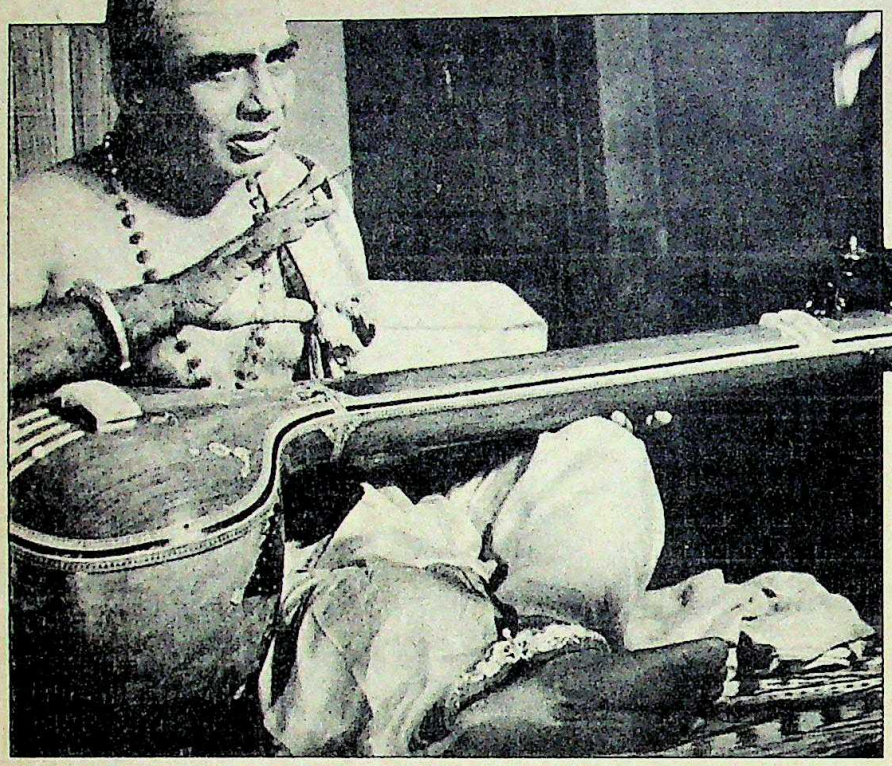

तेलुगु फिल्म 'शंकराभरणम' में वी. सोमयाजुलुः संगीत प्रधान मनोरंजन

भारतीय फिल्मोद्योग को दो-चार होना पड़ रहा है. हालांकि सूचना प्रसारणमंत्री हरकिशनलाल भगत ने 11 मार्च को राज्यसभा में इस बात का खंडन किया कि फिल्मोद्योग भारी घाटे से गुजर रहा है मगर सचाई यह है कि मद्रास में आज केवल दर्जन भर स्टुडियो रह गए हैं. पिछले दस बरसों में 30 से ज्यादा स्टुडियो मालिकों को शटर गिराने पर मजबूर होना पड़ा है. रिलीज न हो पाने वाली फिल्मों की संख्या भी कई गुना बढ़ी है.

फिर भी बदलाव फिल्मोद्योग के हर पहलू में साफ दिखता है. फिल्मों के विषय ज्यादा यथार्थवादी हुए हैं और संवाद आम आदमी की भाषा से जुड़ने लगे हैं. आधुनिक तकनीक और उपकरणों से दृश्य ज्यादा मनोहर हुए हैं. भड़कीले सेटों का भी जमाना अब नहीं रहा. यही हाल सजे-धजे उस हीरो का हुआ जिसकी जगह बस कंडक्टर से अभिनेता बने रजनीकांत ने ले ली है, जो कहते हैं कि वे अपने बाल भी नहीं संवारते. स्टुडियो से निकलकर मूवी कैमरे अब बाहरी लोकेशनों खासकर देहात में ज्यादा घूमते हैं. करीब एक दशक पहले भारती राजा जैसे युवा निर्देशकों ने, जो स्टुडियो का खर्च बरदाश्त नहीं कर सकते थे, इस पहल को गति दी थी. दर्शकों ने भी इसे स्वीकार लिया. नतीजतन स्टुडियो बंद होने लगे और आउटडोर शूटिंग यूनिटों की संख्या बढ़ी. आज मद्रास में करीब 40 ऐसी यूनिटें हैं जो हफ्तों पहले से बुक रहती हैं. फिल्मोद्योग के मौजूदा मिजाज की बाबत निर्देशक मणिरत्नम बताते हैं, "मुझ जैसे निर्देशकों का विचार है कि हम नए 'नाटकीय यथार्थ' को सफलतापूर्वक पेश कर सकते हैं." इसकी वजह वे दर्शकों की रुचि में आए बदलाव को बताते हैं. रत्नम छह साल पहले फिल्मों में आए थे और राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीत चुके हैं. उनकी ताजा फिल्म 'नायकन' इस साल ऑस्कर के लिए भारत की ओर से अधिकृत प्रविष्टि थी. कमल हासन को लेकर बनी यह फिल्म माटुंगा (बंबई) के 'डॉन' वरदराजन मुदलियार के जीवन पर आधारित है और दक्षिण भारतीय फिल्मों में बदलाव का एक बड़ा प्रतीक भी. 'नायकन' के वितरक और साउथ इंडियन फिल्म चैंबर ऑफ कामर्स के अध्यक्ष जी. वेंकटेश कहते हैं, "पुराने फार्मूले अब नहीं रहे. दक्षिण की फिल्में अब हीरो, हीरोइन और विलन की फंतासी पर ही नहीं घूमतीं." लेकिन वे बदलावों का दूसरा पहलू भी सामने रखते हैं, "यह कहना सही नहीं होगा कि दक्षिण कला फिल्में बना रहा है. असल में हमने सही संतुलन बनाया है. अब विषय यथार्थपूर्ण होते हैं, ऐसे जिन्हें आज के दर्शक स्वीकार कर लें." फिल्म में वेलु नायकन की भूमिका निभाने वाले कमल हासन के शब्दों में, "खासकर तमिल फिल्मों में आम लहर ऐसे मनोरंजन की चल रही है जिस पर लोग विश्वास कर सकें. दर्शकों की स्वीकृति ने मुझ जैसे अभिनेताओं को अपनी छवि के साथ प्रयोग करने का भी मौका दिया है."

"अच्छा संगीत तो जैसे लुप्त ही हो गया है. उसकी जगह हिंसा और एक्शन घुस आए हैं. शायद यह आज की तेज रफ्तार जिंदगी का सबूत है. पर ऐसी फिल्में दिलों में नहीं उतरतीं"

के. विश्वनाथ
'शंकराभरणम' के निर्देशक

पिछले एक दशक में दक्षिण भारतीय फिल्मों पर हिंदी की ही तरह हिंसा ने भी हमला किया. मारामारी और गोलियां चलने के दृश्य अब मानो अनिवार्य हो गए हैं. 'शंकराभरणम' जैसी संगीत प्रधान फिल्म के निर्देशक के. विश्वनाथ के शब्दों में, "हिंसा से भरी इन फिल्मों में जान नहीं होती. अच्छा संगीत तो लुप्त ही हो गया है, उसकी जगह हिंसा और एक्शन घुस आए हैं. शायद यह आज की तेज रफ्तार जिंदगी को ही प्रतिबिंबित करता है. पर मैं मारधाड़ वाली ऐसी फिल्मों की बढ़ोतरी से खफा हूं, जो दर्शकों के दिलों की गहराइयों में कतई नहीं उतरतीं." 41 साल से तमिल फिल्मों से जुड़े निर्देशक मुक्ता श्रीनिवासन का भी यही विचार है. "दर्शकों की रुचि पूरी तरह तरह बदल गई है. पारिवारिक ड्रामे की जगह अब हिंसा, बदला और सेक्स ने ले ली है. हालांकि यह कोई स्वस्थ लक्षण नहीं है पर यह एक ऐसा पहलू है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता." ज्यादातर प्रेमकथाओं पर आधारित करीब 60 तमिल फिल्में बना चुके बुजुर्ग फिल्मकार श्रीधर के मुताबिक, "आठवें दशक के मध्य तक लोगों को आम तौर पर प्रेमकथाओं वाली फिल्में पसंद थीं. मगर अब सब बदल गया है.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

फिल्मों में रफ्तार, हिंसा और फाइट सीन जरूरी हो गए हैं. राहत देने के लिए कुछ गीत जरूर रखे जाते हैं पर गंभीर कहानी पूरी तरह गायब हो गई है." श्रीधर ने अनेक नए कलाकारों को फिल्म जगत में स्थापित कराया है. लेकिन उनके मुताबिक, "अब यह जुआ नहीं खेला जा सकता. मैं खुद अब दो जाने-माने कलाकारों— कार्तिक और रेवती को लेकर फिल्म बना रहा हूं."

सत्तर के दशक में रमणीय प्रेमकथाओं वाली अपनी फिल्मों से फिल्म जगत में खलबली मचा देने वाले और तीन बार राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले निर्देशक भारती राजा की भी राय ऐसी ही है. वे कहते हैं, "जब तक निर्देशक सच में मशहूर न हो तब तक नए लोगों को लेकर फिल्म बनाने में जोखिम ही है." राजा की ताजा फिल्म 'वेदम पुडिया' में सत्यराज और सरिता की लोकप्रिय जोड़ी है.

लेकिन शायद सबसे बड़ा बदलाव राजनैतिक संदेश वाली फिल्मों के रूप में आया है. पहले भी सी.एन. अन्नादुरै जैसी राजनैतिक हस्तियों का फिल्मों में सफल इस्तेमाल हुआ है लेकिन पिछले बरसों में राजनीति से सराबोर पटकथाओं ने फिर से जोर पकड़ा. बॉक्स ऑफिस पर एम.करुणानिधि की पटकथाओं को जबरदस्त लोकप्रियता मिली. आज स्थिति यह है कि भारती राजा और के. भाग्यराज सहित बहुत से फिल्मकार राजनैतिक संदेश वाली पटकथाओं पर काम कर रहे हैं.

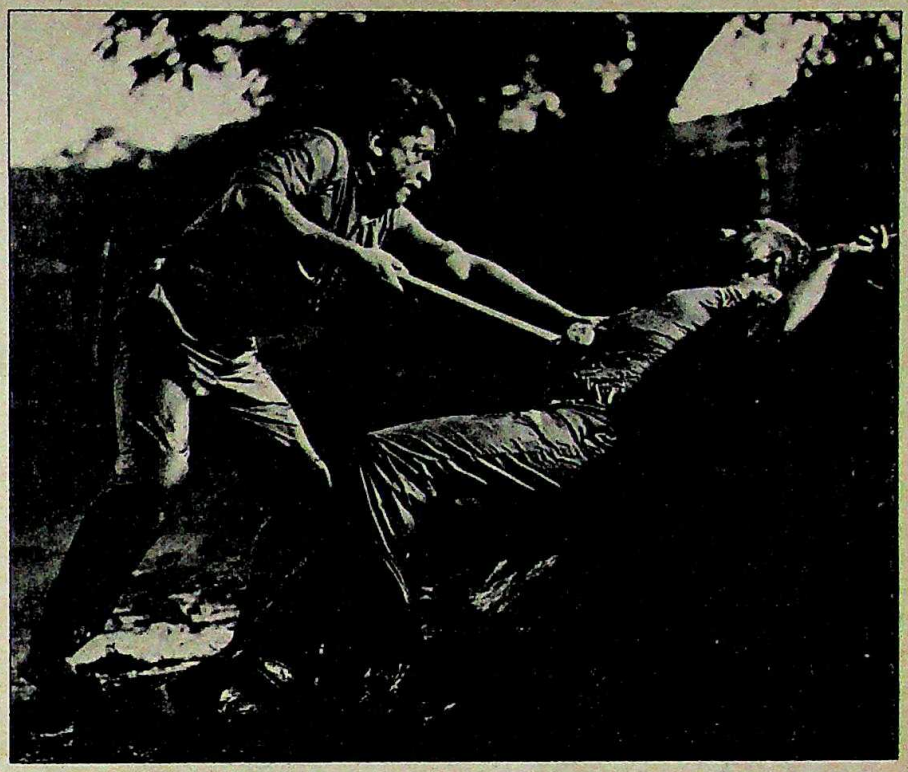

'नायकन' के एक दृश्य में कमल हासन (बाएं): आज का यथार्थ

दक्षिण में फिल्मोद्योग का विस्तार भी पिछले दस सालों में तेजी से हुआ. आज 200 से 300 के बीच फिल्में निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं. लेकिन श्रीनिवासन इस विकास को स्वागतयोग्य नहीं मानते. उनके मुताबिक संख्या जितनी ज्यादा होगी, फिल्मों की असफलता भी उतनी ही बढ़ेगी जो उद्योग के लिए खतरनाक होगा. निर्माता और दक्षिण के सफलतम वितरक एस. धनु कहते हैं कि ज्यादा फिल्में और कम लाभ उद्योग पर बोझ बढ़ाता है. विश्वनाथ के शब्दों में, "अब तो सवाल हर फिल्म के लिए ज्यादा संसाधनों का है. 99.9 प्रतिशत फिल्में लाभ नहीं देतीं, फिर भी निर्माता को अपने अस्तित्व और भरपाई के लिए दूसरी फिल्म शुरू कर देनी पड़ती है. इस तरह फिल्मों की संख्या बढ़ना कोई विकास नहीं है, बल्कि हम वहीं के वहीं घूम रहे हैं." पिछले दशक में कई सौ फिल्में वितरित करने वाले जी. वेंकटेश मानते हैं कि बाकी देश की तुलना में दक्षिण में सबसे ज्यादा फिल्में बन रही हैं पर यह भी तथ्य है कि कमल हासन और और रजनीकांत जैसे सितारों की झोली में 150-150 फिल्में हैं जबकि हिंदी फिल्मों के अमिताभ बच्चन जैसे सुपर सितारे ने भी अब तक के अपने फिल्मी जीवन में 36 से ज्यादा फिल्में नहीं की हैं.

फिल्मों की संख्या बढ़ने से गेट कलेक्शन कई गुना बढ़ा है. 1970-71 में तमिलनाडु में कुल गेट कलेक्शन 21 करोड़ रु. से कुछ ऊपर था. 1986-87 में यह 146.75 करोड़ रु. पर पहुंच गया. टैक्स जो पांच साल पहले 17 करोड़ रु. था, 1986-87 में बढ़कर 76 करोड़ रु. हो गया. इस बढ़ोतरी की वजह आबादी बढ़ना भी है और टिकटों की दरें बढ़ना भी. फेडरेशन ऑफ फिल्म फायनेंसर्स के अध्यक्ष डी. रामानुजम ने बताया, "एक दशक पहले टैक्स 55 प्रतिशत से घटाकर 33.3 प्रतिशत किया गया था. लेकिन पिछले साल इसमें फिर कुछ बढ़ोतरी कर दी गई."

"हम नए 'नाटकीय यथार्थ' को सफलतापूर्वक पेश कर सकते हैं क्योंकि दर्शकों की रुचियां बदल गई हैं. 'नायकन' पूरे दक्षिण भारतीय सिनेमा में आए बदलाव का सटीक प्रतीक है"

मणिरत्नम
'नायकन' के निर्देशक

देश भर में फिल्मों में करीब 1500 करोड़ रु. की पूंजी लगती है जिसकी आधी से अधिक दक्षिण भारतीय फिल्मों में है. फिल्म निर्माण इस तेजी से महंगा हुआ है कि कम बजट की फिल्म भी 30 से 40 लाख रु. की बैठती है और साल में कुछ फिल्में तो एक करोड़ रु. का आंकड़ा पार कर जाती हैं. पिछले पांच साल में इसी हिसाब से अभिनेता-अभिनेत्रियों की कीमत भी बढ़ी है. कमल हासन और रजनीकांत को 25 लाख रुपए के आसपास मिलने लगे हैं तो दूसरे दर्जे के अभिनेताओं को 8-10 लाख रुपए. बड़ी अभिनेत्रियों को भी 4-5 लाख रु. मिलते हैं जिन्हें पहले 50 हजार रुपए में निबटा दिया जाता था. इस बीच दक्षिण भारतीय हीरोइनों का हिंदी फिल्मों में जाना फिर से जोर पकड़ने लगा है. इस मामले में श्रीदेवी और जयप्रदा की सफलता के बाद भानुप्रिया, विजयशांति, राधिका और

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

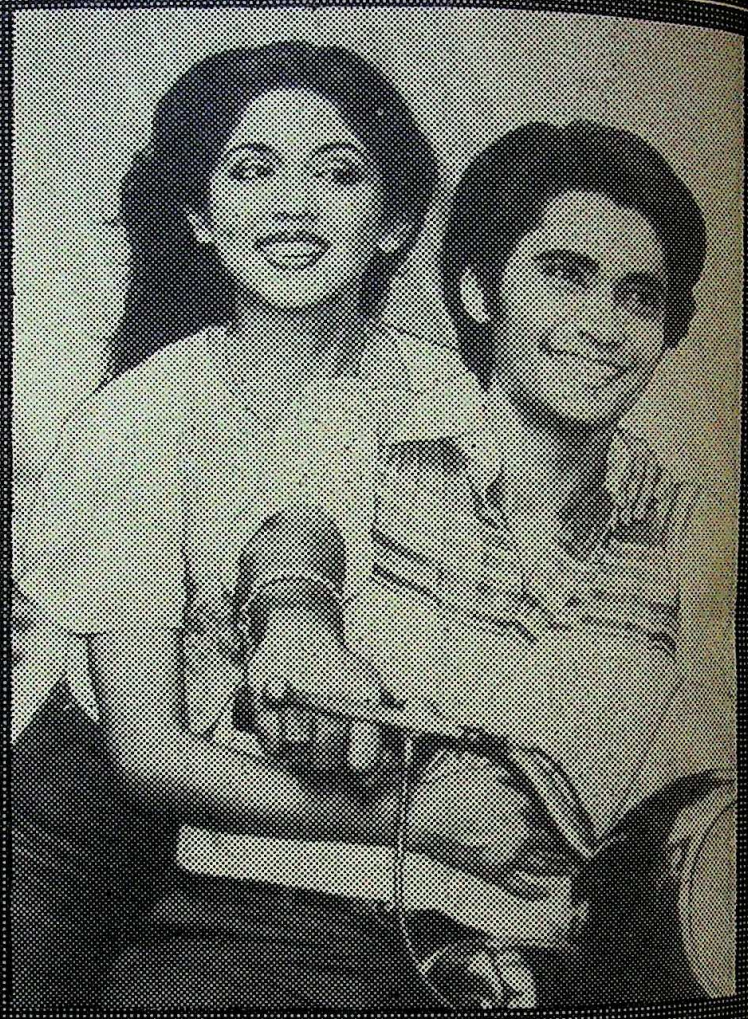

सिर की त्वचा के ख़ुश्क होने का मतलब है आपके बालों के ख़त्म होने की शुरूआत

बाल सबन्धी सभी समस्याओं का कारण सिर की खुश्क त्वचा ही है। डैन्ड्रफ़। बालों के बेचमक और आख़िर में बालों का झड़ना।

०

तभी तो आपके लिए ज़रूरी है वैसलीन हेयर टॉनिक ऐंड स्कालप कंडीशनर। विशेष फ़ार्मूले से तैयार हेयर टॉनिक जो सिर की त्वचा को खुश्क होने से रोकता है।

इतना विशुद्ध और पोषण से भरपूर कि इसकी कुछ बूंदों से ही सिर की संपूर्ण त्वचा को आवश्यक पोषण मिल जाता है।

आपके बाल चिपचिपे नहीं दिखायी देते। सजे-सँवरे और शानदार रहते हैं... हमेशा।

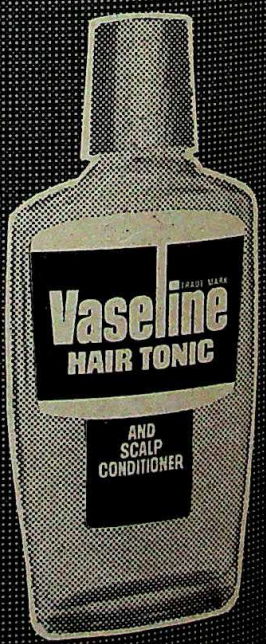

वैसलीन

हेयर टॉनिक
ऐंड स्कालप
कंडीशनर

सही पोषण और देख-भाल
यानी शानदार सजीले बाल

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मिलिए टाफ़े की जोरदार तिकड़ी से-

एम एफ़ १०३५, एम एफ़ २४५ और टाफ़े २५

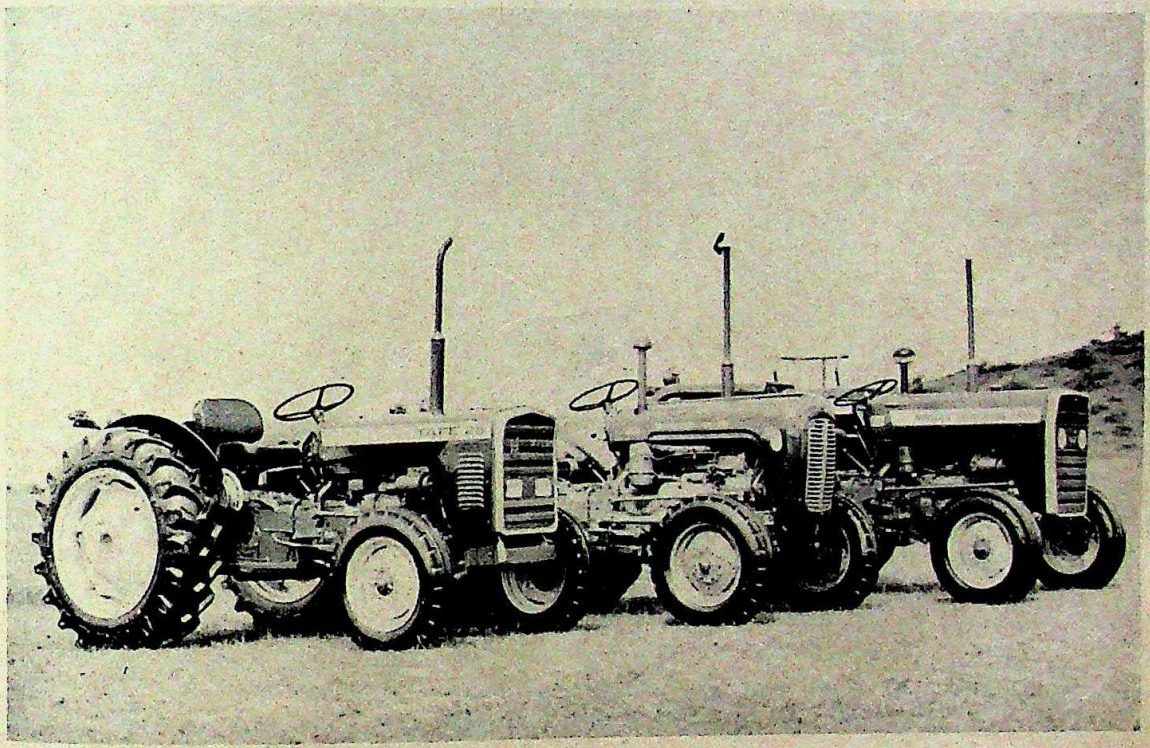

टाफ़े – यानी दुनिया-भर में मशहूर मैसी फ़ेरगुसन ट्रैक्टरों के उत्पादन एवं बिक्री में पहल करने वाली भारतीय कंपनी.

टाफ़े ट्रैक्टर श्रेणी में शामिल हैं एम एफ़ १०३५, एम एफ़ २४५, टाफ़े २५ और नया एम एफ़ १०३५ डी आई – इन सारे ट्रैक्टरों में मौजूद हैं मैसी फ़ेरगुसन टेक्नालॉजी के लाभ. इन ट्रैक्टरों के अनुकूल मैसी फ़ेरगुसन इम्प्लीमेंट्स और एक्सेसरीज़ की विशाल श्रेणी तैयार रुप में उपलब्ध है – ताकि आप अपने खेतों में अलग-अलग कामों के लिए इनका इस्तेमाल कर सकें.

अनोखी फ़ेरगुसन हाइड्रॉलिक प्रणाली से सुसज्जित इन ट्रैक्टरों का नियंत्रण भी आप केवल उंगलियों से कर सकते हैं. इनके साथ आप मैसी फ़ेरगुसन इम्प्लीमेंट्स का उपयोग भी आसानी से कर सकते हैं.

एम एफ़ १०३५ एक ३५ हॉर्स पावर ट्रैक्टर है. जो ऊबड़-खाबड़ ज़मीन पर इस्तेमाल के लिए हर तरह से उपयुक्त है.

एम एफ़ २४५ अपनी अधिक वज़न ढोने की (हॉलिंग) क्षमता के कारण बड़े-बड़े खेतों और बागानों के लिए सर्वोत्तम ट्रैक्टर है.

टाफ़े २५ एक २५ हॉर्स पावर का नया ट्रैक्टर जो छोटे-छोटे खेतों के लिए उत्तम है.

एम एफ़ १०३५ डी आई यानी टाफ़े श्रेणी की नयी कड़ी. इसके डायरेक्ट इंजेक्शन डीज़ल इंजन के कारण यह डीज़ल की अधिक बचत कराए और इसे बनाए एक भरोसेमंद ट्रैक्टर.

भारत-भर में टाफ़े के २०० से भी अधिक बिक्री एवं सेवा केंद्र हैं. इसलिए आप जब चाहें, जहां चाहें इसके स्पेयर पार्ट्स आसानी से हासिल कर सकते हैं.

ट्रैक्टर्स एण्ड फार्म इक्विपमेन्ट लिमिटेड
मद्रास

MASSEY-FERGUSON

TAFE

सभी से आगे- टाफ़े

MAC/TAFE/1053 HIN

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अमला के नाम लिए जा सकते हैं. निर्देशक मणि-रत्नम कहते हैं, "क्योंकि हिंदी फिल्में ज्यादा बनने लगी हैं, सो दक्षिण भारतीय लड़कियों की मांग भी फिर से बढ़ गई है. दक्षिण भारतीय सौंदर्य वैसे भी उत्तर भारतीयों को हमेशा से लुभाता रहा है."

फिल्मों की संख्या कितनी भी बढ़ी हो पर आसमान छूती निर्माण लागत उद्योग पर अपना प्रभाव डाल रही है. ज्यादातर पुराने बैनर भुला दिए गए हैं. और सैकड़ों निर्माताओं में से केवल 20-30 ऐसे हैं जो पूंजी लगाने वाले की जुगाड़ कर सकते हैं. कभी एक प्रतिष्ठित बैनर माना जाने वाला प्रसाद पिक्चर्स अब केवल प्रोडक्शन कार्य करता है. जेमिनी स्टुडियो की जगह अब एक विशाल कमर्शियल कांप्लेक्स बन गया है और नागी रेड्डी की याद भी तभी आती है जब आप विजया अस्पताल के पास से गुजरें. 40 साल पहले गठित एवीएम जरूर किसी तरह गाड़ी घसीट रहा है. शायद इसकी वजह यह है कि उसके स्टुडियो में आधुनिक उपकरण हैं और उसने ऑडियो व वीडियो कैसेटों के क्षेत्र में भी पांव पसार दिए. एवीएम के संस्थापक ए.वी. मेयप्पन के बेटे सरवण कहते हैं, "हम इसे दूसरे धंधों की तरह लेते हैं और कम लाभ के सिद्धांत पर फिल्म बनाते हैं. हम दर्शकों को संपूर्ण मनोरंजन देने वाली फिल्मों के साथ ज्यादा यथार्थवादी फिल्में बनाने लगे हैं." एवीएम की सुपरहिट फिल्म 'संसारम और मिंसारम' को संपूर्ण मनोरंजन के लिए राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक मिल चुका है. एवीएम ने टीवी सीरियल बनाने की ओर भी कदम बढ़ाए हैं और रघुवरन जैसे टीवी स्टार को सफलता पूर्वक फिल्मों में स्थापित किया है.

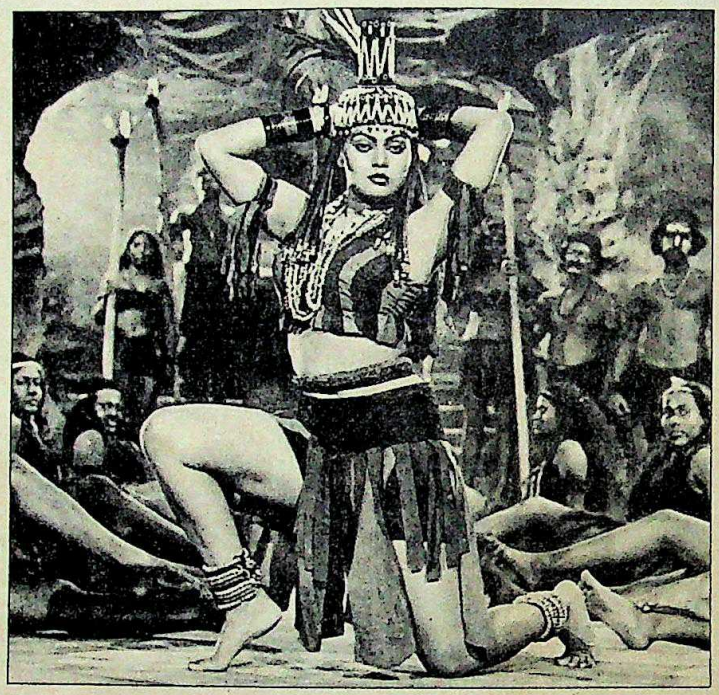

तेलुगु की थ्री-डी फिल्म 'छू मंतर काली' में सिल्क स्मिता: तड़क-भड़क

टीवी और वीडियो का असर भी दक्षिण भारतीय सिनेमा पर पड़ा है. वितरक एस. धनु कहते हैं, "यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि टीवी, वीडियो के कारण 40 प्रतिशत दर्शक कम हो गए हैं. यह सबसे बड़ा खतरा है क्योंकि यह मध्यम व निम्न-मध्यम वर्ग के हर घर में पहुंच गया है. यही फिल्मों का सबसे बड़ा दर्शक वर्ग है. फिलहाल तो तमिल और कुछ हद तक तेलुगु फिल्मोद्योग ही टीवी और वीडियो के हमले का सामना कर पा रहा है."

तेलुगु और मलयाली फिल्मों के साथ भी कमोबेश यही दिक्कतें हैं. एक प्रमुख तेलुगु फिल्म निर्माता डी. रामा नायडू के मुताबिक, "निर्माण लागत उद्योग का कचूमर निकाले दे रही है. पैसा वापस निकलना मुश्किल होने से करीब 50 फिल्में डिब्बों में पड़ी हैं." तेलुगु फिल्में अपने भव्य, मनोरम सेट्स और समग्र निर्माण तकनीक के लिए मशहूर हैं लेकिन अब यदि निर्माता बॉक्स ऑफिस पर उनको कामयाब नहीं पाते तो यह ढंग बदल भी सकता है. मलयाली निर्माता ए. कट्टराकारा कहते हैं, "फिल्मों की संख्या हर साल गिरती जा रही है. 1987 में केवल 65 फिल्में रिलीज हो पाईं. अगर कोई चमत्कार नहीं होता तो देश के इस 'शिक्षित' राज्य में फिल्मोद्योग समाप्त ही हो जाएगा." लेकिन उधर कन्नड़ फिल्मोद्योग, जिसे राज्य सरकार की रियायतों का लाभ मिला है, मौजूदा संक्रमण काल में एक संतुलन बिठाने की कोशिश में लगा है. 70-80 फिल्मों में हीरो रह चुके बी. विष्णुवर्धन कहते हैं, "हमारा उद्योग बंगलूर के आसपास केंद्रित है जहां केवल 40 प्रतिशत आबादी ही स्थानीय है. यहां के सभी लोगों को आकर्षित करे ऐसी फिल्म बनाना एक मुश्किल काम है. फिर बंगलूर में विदेशी फिल्में भी ज्यादा लगती हैं. ऐसे में किसी कन्नड़ फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर हिट होना एक बड़ी उपलब्धि है." शायद इसीलिए कन्नड़ फिल्मकार दूसरी भाषाओं की सफल फिल्मों के रीमेक बनाने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं.

"वास्तव में पिछले दशक से अब तक दक्षिण भारतीय फिल्मोद्योग में भारी बदलाव आए हैं," 38 साल से फिल्मों (कुल 200 से ऊपर) में हीरोइन रहीं और अब चरित्र अभिनेत्री सावकार जानकी कहती हैं, "दर्शक पुराने विषयों को स्वीकार नहीं करते. उन्हें हमेशा कुछ नए की तलाश रहती है. पहले स्टार सिस्टम के अगुआ थे एमजीआर और शिवाजी गणेशन, अब उनकी जगह निर्देशक और टेक्नीशियन हैं. हालांकि यह स्वागतयोग्य है पर अभिनेता-अभिनेत्रियों के काम में गिरावट आई है जो मुझे निराश करती हैं." लेकिन वे मुस्कराती हैं. "फिल्म उद्योग पूरी तरह जिंदा है और इसका हिस्सा बनकर मुझे खुशी होती है. मैं कभी रिटायर नहीं हो सकती." यह बुजुर्ग अभिनेत्री आज भी तमिल और दूसरी दक्षिण भारतीय भाषाओं की फिल्में कर रही हैं.

और सचमुच उन जैसे बहुत से लोग हैं. तमाम दिक्कतों के बावजूद दक्षिण भारतीय फिल्मोद्योग के युवा कलाकारों, निर्देशकों और टेक्नीशियनों की उम्मीदें मरी नहीं हैं, हौसले पस्त नहीं हुए हैं. वे टीवी, वीडियो और बढ़ती निर्माण लागत का मुकाबला करने को तैयार हैं.

—ललिता बिलीय

पारिवारिक ड्रामे की जगह अब हिंसा, बदला और सेक्स ने ले ली है. गंभीर कहानी तो पूरी तरह गायब हो गई है पर फाइट सीन और अश्लील नृत्यों वाले गीत जरूरी हो गए हैं

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'हवाई हमले' का बिल कौन भरे

मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के पैरों तले की जमीन खिसकाने के लिए केंद्रीय मंत्री मोतीलाल वोरा और माधवराव सिंधिया ने हाल ही में संयुक्त रूप से 'हवाई हमले' किए और अपनी मुहिम की कामयाबी से संतुष्ट होकर लौटे. लेकिन झंझट यह पैदा हो गया है कि दोनों नेताओं ने राज्य के दूरदराज इलाकों की जो हवाई यात्राएं कीं उसका दो लाख रुपए का बिल कौन भरेगा.

ये यात्राएं न तो पार्टी के काम से की गईं और न ही सरकारी

राजेश जैन

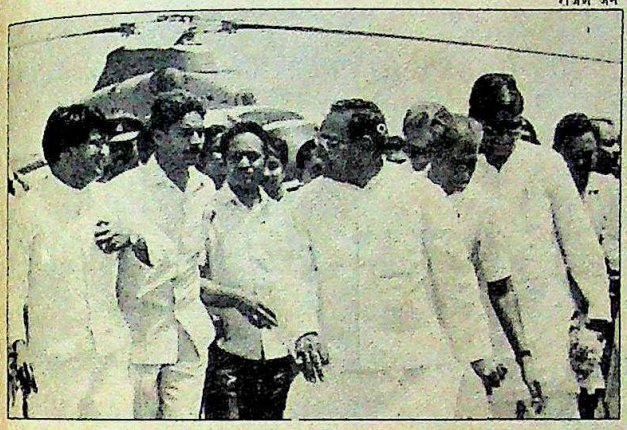

भोपाल हवाई अड्डे पर वोरा और सिंधिया: टालमटोल

काम से. शुरू में यह दिखाने की कोशिश की गई कि इन यात्राओं को पार्टी आलाकमान ने मंजूरी दी थी और यह कि इनका हिसाब-किताब अखिल भारतीय कांग्रेस (इ) कमेटी निबटाएगी. जब रेलमंत्री सिंधिया से पूछा गया कि हेलीकॉप्टर कार्पोरेशन से किराए पर लिए गए हेलीकॉप्टर के बिल का भुगतान कौन करेगा तो उन्होंने कहा, "सीताराम केसरी (पार्टी कोषाध्यक्ष) से पूछिए." लेकिन बाद में पता चला कि हेलीकॉप्टर पार्टी ने नहीं, बल्कि नागरिक उड्डयनमंत्री वोरा ने मंगवाया था. लिहाजा लगता है कि वोरा को ही बिल भरना पड़ेगा. लेकिन फिलहाल तो दोनों मंत्री इस मामले को किसी तरह टालने की फिराक में ही दिख रहे हैं.

सबूत के बावजूद

प. बंगाल के पिछले विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने आरोप लगाया था कि वाम मोर्चा सरकार सिर्फ अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं, समर्थकों के लाभ के लिए काम करती है. माकपा ने इस बयान की आलोचना की तो प्रदेश इंका अध्यक्ष प्रियरंजन दासमुंशी को जवाब देना मुश्किल हो गया.

लेकिन पिछले पखवाड़े इंका विधायक सोमेन मित्रा ने मुख्यमंत्री ज्योति बसु के विशेष सहायक द्वारा लिखी एक चिट्ठी विधानसभा में लहराते हुए वही आरोप दोहराया. इस चिट्ठी में हुगली जिले के चोपा गांव के एक ग्रामीण की शिकायत के जवाब में कहा गया था, "आपके आरोपों की मुख्यमंत्री के आदेश पर जांच की गई. चूंकि आपने माकपा की जिला शाखा के सवालों का सही जवाब नहीं दिया, लिहाजा मामला नहीं सुलझाया जा सका."

मित्रा: जोरदार आरोप

इस चिट्ठी से बसु परेशान दिखे. उन्होंने यह कहकर स्थिति को संभालने की कोशिश की कि ग्रामीण ने ठीक से काम न करने वाले अपने खेतिहर मजदूरों के खिलाफ शिकायत की थी. उन्होंने यह भी कहा कि वे उन मजदूरों की पिटाई के लिए पुलिस को आदेश नहीं दे सकते थे. इस पर मित्रा ने कहा, "शिकायत चाहे जैसी भी हो, प्रशासन किसी परेशान ग्रामीण को सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं से न्याय मांगने के लिए क्यों कहे?"

फव्वारों में आई थोड़ी देर जान

सूखाग्रस्त राजस्थान की राजधानी जयपुर के असंख्य फव्वारे पिछले पखवाड़े फिर फुहार छोड़ने लगे. लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि इंद्र देवता खुश हो गए या कि शहर में पानी का संकट खत्म हो गया. यह तो राजीव महिमा का चमत्कार है. वे जिलाधीशों और सेवादल के कार्यकर्ताओं की अलग-अलग बैठक में भाग लेने के लिए 20 घंटे के लिए जयपुर क्या गए कि सभी फव्वारे जी उठे.

जयपुर वालों को यह फिजूलखर्ची भाई नहीं. लेकिन एक सांत्वना थी कि हर फव्वारे पर तैनात मालियों ने जब प्रधानमंत्री का काफिला आते देखा तो फव्वारा चालू कर दिया. और काफिला गुजरते ही फव्वारा बंद कर दिया. इतना ही नहीं, कुछ मालियों ने तो काफिले की आखिरी कार गुजरने के पहले ही फव्वारा बंद कर दिया.

राजीव को भीड़ के मामले में भी गुमराह किया गया. सड़क के दोनों ओर चिलचिलाती धूप में लोग अपने राजनैतिक झुकाव के कारण नहीं बल्कि पुलिस के कारण खड़े थे. पुलिस ने काफी पहले से ही सड़कों पर घेरा डाल दिया था. लोगों को देख जब राजीव ने उत्साह से हाथ हिलाया तो जले पर नमक ही पड़ा. दो घंटे से वे पसीने से सराबोर जो हो रहे थे.

राजनीति के पिच पर

क्रिकेट खिलाड़ी कीर्ति आजाद ने अब एक नए मैदान पर नई पारी शुरू की है. पिछले पखवाड़े कीर्ति ने अपनी इस पारी—राजनैतिक पारी— की शुरुआत भागलपुर में एक सरकारी समारोह में की जिसमें उनके पिता मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद मौजूद थे.

आम तौर पर जींस और टी-शर्ट पहनने वाले कीर्ति उस दिन खादी वस्त्रों में थे. जब उन्होंने हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया तो युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता खासे उत्साहित दिखे. मजेदार बात तो यह है कि बिहार सरकार के सूचना और लोकसंपर्क विभाग ने इस घटना पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की.

कृष्णमुरारी किशन

कीर्ति : नई पारी

लोग-बाग अपनी समस्याओं को लेकर कीर्ति के पास पहुंचने भी लगे हैं. कीर्ति को 'लोगों की समस्याओं' पर अधिकारियों, मंत्रियों और पार्टी नेताओं से चर्चा करते देखा जाता है. मुख्यमंत्री आजाद को इसमें कुछ गलत नहीं दिखता वे कहते हैं, "यदि पत्रकार और सरकारी अधिकारी के बेटे अपने पिता के चरण चिन्हों पर चल सकते हैं तो किसी राजनीतिक का बेटा क्यों नहीं?"

मुख्यमंत्री कहते हैं कि "राजनीति में प्रवेश करने के लिए कीर्ति को खुद अपना रास्ता बनाना होगा." लेकिन इतना तो साफ है कि हाल के सरकारी समारोह में कीर्ति को अपने पिता के कारण ही बुलाया गया. और मौके का चुनाव भी कितना माकूल है! कीर्ति ने अपने पिता के मुख्यमंत्री बनते ही राजनीति में कदम रखे. और पिता ने अपने बेटे के लिए एक सुरक्षित संसदीय सीट खाली कर दी.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बीरबहादुर सिंह

सत्ता और संपर्क की सटीक समझ

विरोधियों को पछाड़ने और मुश्किलों पर काबू पाने में माहिर

बीरबहादुर सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कोई 950 दिन पूरे कर लिए. 1967 से अब तक का यह एक रिकार्ड है. कमलापति त्रिपाठी 800 दिन, हेमवतीनंदन बहुगुणा 754 दिन, नारायणदत्त तिवारी 465 दिन, बनारसीदास गुप्त 354 दिन, विश्वनाथ प्रताप सिंह 769 दिन और श्रीपति मिश्र 745 दिन तक इस कुर्सी पर रहे. बीरबहादुर के शासनकाल में कई मुश्किलें आईं पर विरोधियों को उन्होंने अपनी चालों से मात कर दिया. उनके व्यक्तित्व पर प्रमुख संवाददाता ***दिलीप अवस्थी*** *का आलेख:*

गद्दीदार सोफे पर बेचैनी से करवटें बदलते और ठेठ गोरखपुरिया लहजे में सुस्ती से बातें करने वाले उस स्थूलकाय और सांवले रंग के व्यक्ति को देखकर लगता है कि वह कोई महत्वाकांक्षीरहित पटवारी है. उसमें चतुराई के कहीं कोई लक्षण नहीं दिखते—दूर-दूर तक नहीं. लेकिन बेचैनी झलकाते इस निस्तेज चेहरे के पीछे छिपा हुआ है अपने को बचाए रखने का दृढ़ इरादा. यह चेहरा है 53 वर्षीय बीरबहादुर सिंह का, जो देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले और समस्याग्रस्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पिछले 31 महीने से जमे हुए हैं. वे बड़ी मासूमियत भरी सफाई देते हैं, "प्रधानमंत्री का मुझमें भरोसा है और इसी कारण राज्य में स्थिर सरकार है."

लेकिन उनके विरोधियों के लिए यह रहस्य ही है कि इस निष्प्रभ नेता ने किस तरह प्रधानमंत्री का भरोसा हासिल कर लिया. उनके खाते में प्रशासनिक या राजनैतिक उपलब्धि के नाम पर कुछ है नहीं. दरअसल, उनके चलते राज्य में भारी उथल-पुथल होती रही है. मेरठ के हत्याकांड सहित 37 जिलों में सांप्रदायिक हिंसा हुई जिनमें 181 लोगों की जान गई, अयोध्या का राम जन्मभूमि मंदिर खुला जिससे पूरे देश को हिला देने वाला सांप्रदायिक भूकंप आ गया, राज्य सरकार के 16 लाख कर्मचारी दो बार लंबी हड़ताल पर गए और सिनेमा मालिकों और दूसरे तबके के लोगों की 29 हड़तालें हुईं, राज्य में शताब्दी का सबसे भयंकर सूखा पड़ा और महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व वाले किसान आंदोलन ने समूची ग्रामीण आबादी को अपनी चपेट में ले लिया.

राजनैतिक रूप से भी, मुख्यमंत्री को ऐसे कई झटके झेलने पड़े कि सत्तारूढ़ पार्टी भी हिलती दिखी. जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने पिछले साल अप्रैल में केंद्रीय मंत्रिमंडल छोड़ा और वे कांग्रेस में बगावत की अगुआई करने पर आमादा दिखे तो राज्य में 100 से ज्यादा विधायकों ने उनके सम्मान में एक भोज आयोजित कर डाला. इससे भी बुरा उस समय हुआ जब चार मंत्री और 18 दूसरे विधायक इस्तीफा देकर विश्वनाथ प्रताप सिंह के जनमोर्चा में चले गए.

लेकिन बीरबहादुर इन तमाम परेशानियों से जिस तरह उबरे, उससे उनके विरोधियों को बहुत ताज्जुब हुआ. जब 24 सितंबर 1985 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला तो बाजी लगाई जा रही थी कि वे दो महीने के भीतर राज़नीति के गर्त में समा जाएंगे. जब भी कोई संकट आता, लगता उनकी कुर्सी गई. लेकिन हर बार उन्होंने साबित कर दिया कि तमाम अफवाहें अतिशयोक्तिपूर्ण है. उनके जो विरोधी कभी कहते थे कि उनकी कुर्सी छिन जाएगी, वही अब गुस्से में चिल्लाते हैं कि उन्हें 'जाना ही चाहिए.'

लेकिन अपने को 'जुझारू' कहने वाले मुख्यमंत्री मैदान छोड़ने वालों में से नहीं हैं. वे कहते हैं, "मैंने यह हैसियत पाने के लिए लगभग 30 साल तक संघर्ष किया है." 1980 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किए जाने तक इंका की कलहभरी राजनीति में उनकी कोई पहचान नहीं थी. लिहाजा, जब वे मुख्यमंत्री बनाए गए तो लोगों को ताज्जुब हुआ. उनके भौंडे आचार-व्यवहार और उनकी सामान्य पृष्ठभूमि के कारण उनके अपने मंत्रियों सहित कई लोगों को लगा उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर सिर्फ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

• सभी फोटो भवान सिंह

इलाहाबाद में पदयात्रा करते बीरबहादुर सिंह

स्थायी व्यवस्था की गई है. उनका विश्वास
कि बीरबहादुर को अरुण नेहरू ने, जो
समय पार्टी में सबसे अधिक ताकतवर
क्ति माने जाते थे, राजीव गांधी की
निच्छा के बावजूद राज्य पर थोप दिया.
और मुख्यमंत्री बनते ही बीरबहादुर ने
क्ष लिया कि गद्दी कैसे बचाए रखनी है.
होंने ऐसी चाल चली कि उनके आलोचक
र्टी से निकाल दिए गए. फिर उन्होंने
चाई से विपक्षी नेताओं में फूट डाली.
श्वनाथ प्रताप सिंह के उदय के पहले ही
रबहादुर हवा के रुख को ऐसा मोड़ देने में
क्ष रहे जिससे उनके असंतुष्टों, खासकर
जय सिंह और सुनील शास्त्री पर विश्वनाथ
ताप का आदमी होने का ठप्पा लग जाए.
गस्त 1987 में इन दोनों को नकवी और
ट्टू सिंह के साथ इस्तीफा देना पड़ा. संजय
ह कहते हैं, "मैं उनके प्रति सिर्फ कृतज्ञ ही
ही सकता हूं क्योंकि वे न होते तो शायद मैं
ा कभी छोड़ नहीं पाता. वे ऐसे मुख्यमंत्री
जिनके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि वे हमेशा
त्तर प्रदेश की कुर्सी पर बने रहें."

उन्होंने विपक्ष को बांटने के लिए भी बड़ी
कुशलता से चालें चलीं. उन्होंने उस समय
विधानसभा में विपक्ष के नेता मुलायम सिंह
यादव को पटाया. वे यादव से अपने चैंबर में
घंटों बातें करते. यादव जो भी चाहते उनसे
करवा लेते. इंकाई हलकों में यह मजाक चल
पड़ा था कि यदि किसी को कोई काम
करवाना हो तो उसे विपक्ष के नेता के पास
जाना चाहिए. मुख्यमंत्री ने तमाम आलोच-
नाओं के बावजूद अपनी इस रणनीति को
नहीं छोड़ा. विपक्ष के नेता सत्यपाल यादव

बीरबहादुर ने मुख्यमंत्री बनते ही समझ लिया कि गद्दी कैसे बचाए रखनी है. ऐसी चाल चली कि उनके आलोचक पार्टी से निकाले गए और विपक्ष में भी फूट पड़ गई

कहते हैं, "हम जानते हैं कि हम (विपक्ष) कई मुद्दों पर सरकार को नीचा नहीं दिखा सके क्योंकि हम बंटे हुए थे. मुख्यमंत्री ने किसी सत्ताधारी दल के नेता के हिसाब से सबसे सही काम यह किया कि हममें से कुछ को फोड़कर अपनी ओर मिला लिया. इससे सबक लेना हमारी जिम्मेवारी बनती है."

लेकिन अपनी राजनैतिक व्यस्तताओं के कारण बीरबहादुर ने अपने प्रशासनिक काम-काज की उपेक्षा ही की है. यादव कहते हैं, "बीरबहादुर अपनी गद्दी बचाने के सिवाय कुछ नहीं सोचते. और यही उनकी उपलब्धि है." नौकरशाह भी इस बात से सहमत हैं. सचिवालय के एक अधिकारी कहते हैं, "मुख्यमंत्री का जब दरबार चल रहा होता है तो उनसे मिलने के लिए हमें कई बार घंटों इंतजार करना पड़ता है." बीरबहादुर चाहे घर में हों या दफ्तर में, खादीधारी लोगों—मंत्री से लेकर ग्राम प्रधानों, यहां तक कि पत्रकारों—से हमेशा घिरे रहते हैं. ये लोग मुख्यमंत्री के चारों तरफ बैठे रहते हैं जबकि अधिकारी उनका इंतजार करते रहते हैं. आगंतुकों से मुख्यमंत्री के मिलने का आलम यह है कि हाल ही में मुख्यमंत्री से मिलने को बेताब एक अधिकारी से बड़ी रुखाई से कहा गया कि "आप तुरंत यहां से हटिए" ताकि मुख्य-मंत्री आगंतुकों के साथ गपशप जारी रख सकें.

राज्य में जिस तरह से आंदोलनों से निबटा जाता है उसमें भी असंवेदनशीलता दिखाई पड़ती है. राज्य सर-कार के कर्मचारियों की नवंबर 1986 और सितंबर 1987 में हुई हड़तालों को लंबे समय तक चलने दिया गया. इनमें से हर हड़ताल लगभग तीन-तीन हफ्ते तक चली. इस मामले में भी बीरबहादुर की बहुत साधारण रणनीति थी—'संकट बढ़ने दीजिए, मजदूर संघों में असंतोष भड़कने दीजिए, फिर उलटा प्रहार करने के लिए उचित मौके का इंतजार करिए.'

राज्य सरकार के कर्मचारियों ने पहली हड़ताल से सरकारी कामकाज ठप हो गया तो मुख्यमंत्री ने हड़ताल को गैरकानूनी घोषित करते हुए उसे राजनीति से प्रेरित बताया. बाद में आंदोलनकारियों पर दमनचक्र चलवा दिया. दूसरी हड़ताल से भी वे ऐसे ही निबटे. हड़तालियों के पस्त होने के लिए वे पूरे 21 दिन इंतजार करते रहे. फिर एक छोटी यूनियन—सचिवालय अधिकारी संघ—से समझौता कर लिया और हड़तालियों की एकजुटता भंग कर दी. पर इससे सरकार को कोई फायदा नहीं हुआ. मुख्यमंत्री ने कर्म-चारियों को 748.50 न्यूनतम वेतन देना मान लिया. जबकि कर्मचारी न्यूनतम 750 रु. की मांग कर रहे थे.

भाजपा विधायक दल के नेता कल्याण सिंह कहते हैं, "वे हर समस्या को भयंकर बन जाने देते हैं. तब उसके सामने समर्पण कर देते हैं. ऐसा वे केंद्रीय नेताओं के सामने यह साबित करने के लिए करते हैं कि इस राज्य को तो बस वे ही चला सकते हैं." एक वरिष्ठ अफसर कहते हैं, "वे किसी समस्या पर तुरंत अपनी प्रतिक्रिया नहीं देते. वे पहले उसकी कमजोरियां ढूंढते हैं और फिर उसे राजनैतिक रंग देते हैं. इन्हीं दो फार्मूलों पर वे काम करते

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हैं.'' उन्होंने मार्च '86 में भड़के दंगों के लिए विश्व हिंदू परिषद पर, मेरठ दंगों के लिए केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवई पर, सिनेमाघर के मालिकों की हड़ताल के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह पर, राज्य सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल के लिए अपने मंत्रिमंडल के कुछ साथियों पर और महेंद्र सिंह टिकैत के मेरठ में 25 दिनों के धरने के लिए इंकाई जाट लॉबी पर दोष मढ़ा.

बीरबहादुर दोष मढ़ने में जितने उदार हैं, अपने कैबिनेट सहयोगियों को सत्ता में हिस्सा देने के प्रति उतने ही अनुदार. वे 72 विभागों के 26 संविभाग अपने पास रखे हुए हैं. दूसरे कई विभाग भी उनकी मुट्ठी में हैं. महत्वाकांक्षी मंत्रियों पर अंकुश रखने के लिए उन्होंने उन्हें ऐसे अधिकारी दे दिए जो मंत्री को पश्चिम दिशा में चलते देख पूर्व की ओर मुड़ जाएं.

केंद्र के सत्तारूढ़ परिवार के प्रति वफादार बने रहकर बीरबहादुर ने जोड़-तोड़ के अपने मनपसंद खेल में अपने मुख्य मोर्चे को साफ रखा है. केंद्र की नजर में अच्छे बने रहने के लिए वे इतने उत्सुक रहते हैं कि लगभग अपने आधे दिन राजधानी में ही बिताते हैं. इस साल के पहले चार महीने में वे 58 दिन दिल्ली में रहे. अप्रैल में उनकी यात्राओं पर एक नजर तो डालिए: वे 11 अप्रैल की सुबह दिल्ली के लिए उड़े और 13 की रात वापस आ गए, फिर दूसरे दिन सवेरे उड़े और 15 की रात वापस आ गए, फिर 16 अप्रैल की सुबह उड़े और चार दिन बाद लौटे, फिर दूसरे दिन उड़े और अगले चार दिन तक लखनऊ में दिखाई नहीं पड़े जब सत्ता के केंद्र के साथ मुख्यमंत्री के संवाद इतने सुचारुपूर्ण तरीके से चलते हों

विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ: चुनावी जंग की तैयारी

फोटो: सूचना विभाग

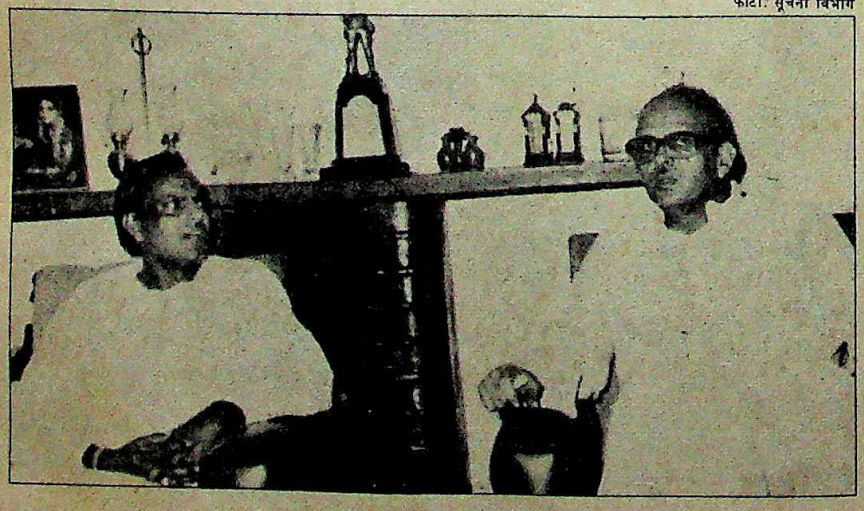

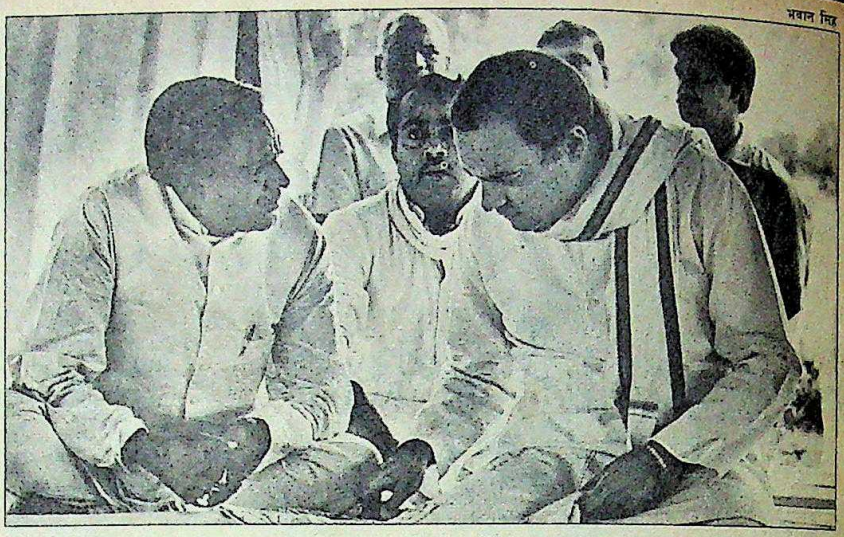

भवान सिंह

अमेठी में राजीव गांधी के साथ: नेहरू परिवार के प्रति निष्ठा

जिस काबिलियत से वे 31 महीने निकाल ले गए वह उन्हें चुनावी जीत तो दिला देगी मगर राज्य के लिए इसका अर्थ सिर्फ प्रशासनिक अराजकता को और बढ़ाना ही होगा

तो वे बड़े मजे से छोटी-मोटी ताकतों की उपेक्षा कर ही सकते हैं.

और यह बात उस समय स्पष्ट हो गई जब पिछले दिनों दिल्ली का एक खादीधारी नौजवान किसी पुलिस अधिकारी के तबादले के लिए ताकतवर माने जाने वाले अखिल भारतीय इंका कमेटी के एक पदाधिकारी की सिफारिशी चिट्ठी के साथ बीरबहादुर से मिलने आया था. उसने चिट्ठी मुख्यमंत्री को थमा दी. उस समय मुख्यमंत्री का दरबार चल रहा था. उन्होंने चिट्ठी पढ़ी और नौजवान को अपने बगल की कुर्सी पर बैठ जाने को कहा. गपशप फिर चलने लगी. अचानक किसी और ख्याल में खोए उन्होंने इंकाई नेता की उस चिट्ठी को लपेटा और उससे कान साफ करने लगे. कान साफ करने के बाद उसे नीचे रखी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया. एकाएक वे उस नौजवान की तरफ मुड़े, ''ठीक है अब आप जा सकते हैं. देखेंगे कि क्या किया जा सकता है.''

विश्वनाथ प्रताप सिंह की राजनैतिक चुनौती की चर्चा होते ही लड़ने-भिड़ने के मूड में आ जाते हैं. वे कहते हैं, ''कौन हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह?'' उनका कहना है कि जनमोर्चा नेता का कोई समर्थक नहीं है. वे कहते हैं, ''वी.पी. सिंह को मैं इस राज्य में आज तक पैदा हुए सभी राजनैतिक नेताओं से कमजोर मानता हूं.'' इलाहाबाद के आगामी उपचुनाव में वी.पी. सिंह द्वारा अमिताभ बच्चन को उम्मीदवार बनाने के लिए इंका को दी गई चुनौती पर मुख्यमंत्री का कहना है कि उनकी पार्टी के संसदीय बोर्ड ने अमिताभ की उम्मीदवारी पर कभी सोचा भी नहीं. वे कहते हैं, ''वी.पी. सिंह को उनकी ही किसी पसंदीदा सीट पर इंका उम्मीदवार के खिलाफ लड़ने दीजिए.''

जाहिर है कि मुख्यमंत्री को यकीन है कि जिस जोड़-तोड़ की काबिलियत के भरोसे वे उथल-पुथल से भरे 31 महीने निकाल ले गए वही काबिलियत उन्हें चुनावी लड़ाई में भी जीत दिलवा देगी. लेकिन राज्य के लिए इसका अर्थ सिर्फ प्रशासनिक अराजकता और बढ़ना ही होगा.

—दिलीप अवस्थी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गर्मियों में जब आपकी त्वचा महसूस करे कांटों-सी चुभन...

तब चुभन हटाए राहत का एहसास दिलाए

नया क्यूटीक्युरा

प्रिकली हीट पाउडर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Orbit/MP—PHP/147-87—H

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मंत्रिमंडल सचिवालय

सर्वोच्च सत्ता का नया शिखर

इसी 'सुपर मंत्रिमंडल' के जरिये प्रधानमंत्री की हुकूमत चलती है

केंद्र सरकार के करीब 80 विभागों के जो भड़कीले नाम हैं उनके आगे मंत्रिमंडल सचिवालय नाम बिलकुल प्रभावहीन, ग्लेमरहीन लगता है. इसका दफ्तर भी, जो राष्ट्रपति भवन के दक्षिणी सिरे पर प्रधानमंत्री के दफ्तर से महज 200 गज दूर है, कोई खासियत लिये नहीं दिखता. इसके 100 से ज्यादा अधिकारी भी नौकरशाह बिरादरी के ही साधारण सदस्य जैसे दिखते हैं.

लेकिन यह आंखों का धोखा भी हो सकता है क्योंकि पिछले तीन सालों में मंत्रिमंडल सचिवालय गुपचुप तरीके से ही सही पर केंद्र सरकार का सबसे मजबूत अमला बन गया है और देश के किसी भी दूसरे बड़े प्रतिद्वंद्वी संगठन को पछाड़ देने की हैसियत में पहुंच गया है. यह एक ऐसा संगठन बन चुका है जिसके जरिये प्रधानमंत्री अपनी हुकूमत चलाते हैं और अपने मंत्रियों से सलाह किए बगैर उनके सुझावों को नजरअंदाज कर सकते हैं या खारिज भी कर सकते हैं. इसकी वजह यह है कि इस सचिवालय का ढांचा ही कुछ इस तरह खड़ा किया गया है कि यह सुपर मंत्रिमंडल की तरह काम कर सकता है और किसी भी विभाग में या उसके जरिये कोई भी फैसला लागू करवा सकता है.

कागज पर तो इसका काम मंत्रिमंडल की मदद करना है पर असल में इसके नाखून हर बोटी में गड़े हैं. मामला चाहे घरेलू राजनैतिक गतिविधियों का हो या अंतरराष्ट्रीय खुफियागीरी का या नाजुक आर्थिक फैसलों का, हर मामले में इसकी दखल है, यहां तक कि जवाहरलाल नेहरू के जन्मशती समारोह और आजादी की चालीसवीं सालगिरह मनाने की तैयारियां करने वाली उच्चस्तरीय कमेटी भी इसी के तहत काम करती है.

इसके 'लोग' हर सरकारी संगठन में तैनात कर दिए गए हैं, चाहे वह गृह मंत्रालय हो या कहीं का भारतीय दूतावास. इस सचिवालय के मातहत एक खुफिया एजेंसी भी है जिसके जरिये यह किसी भी सरकारी अधिकारी या राजनीतिक का कैरियर बना या बिगाड़ सकता है. एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री भी मानते हैं, "पहले के मुकाबले अब यह विभिन्न मंत्रालयों के साथ ज्यादा संपर्क करने लगा है. यह तो नहीं कहा जा सकता कि इसकी भूमिका बढ़ गई है पर इतना साफ है कि अब यह ज्यादा सक्रिय है."

यह सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है. इसका मुख्य काम है प्रधानमंत्री के फैसलों को प्रभावित करने वाले हर मुद्दे पर जानकारियां इकट्ठी करना और मिलान व विश्लेषण करना. इस सचिवालय में आजकल विज्ञान, अर्थशास्त्र और प्रबंधन क्षेत्र के नए सितारों का बोलबाला है. और यह प्रधानमंत्री की सहायता के लिए एक सलाहकार विद्वत मंडली की तरह काम करने लगा है.

सचिवालय की बढ़ती हुई भूमिका 1985 में तब जाहिर हुई जब कई वरिष्ठ अधिकारी इसके अमले में शामिल किए गए. आज इसमें एक दर्जन से भी ज्यादा ऐसे अधिकारी हैं जिनका दर्जा राज्यमंत्री या केंद्र सरकार के सचिव के बराबर है. इस तरह आज यह सरकार का सबसे ज्यादा आला अफसरों वाला संगठन बन गया है.

इसकी हैसियत इस बात से भी जाहिर होती है कि रक्षा मंत्रालय के बाद यही एक ऐसी सरकारी एजेंसी है जो आधा दर्जन से ज्यादा विमान इस्तेमाल करती है. इनमें तीन बोइंग 707 तो इसने पिछले साल एअर इंडिया से खरीदे थे. इसके वरिष्ठ अधिकारियों ने देश भर के 800 'रेक्स' टेलीफोन में से 100 हथिया लिए हैं.

चार्ट: बी.के. शर्मा

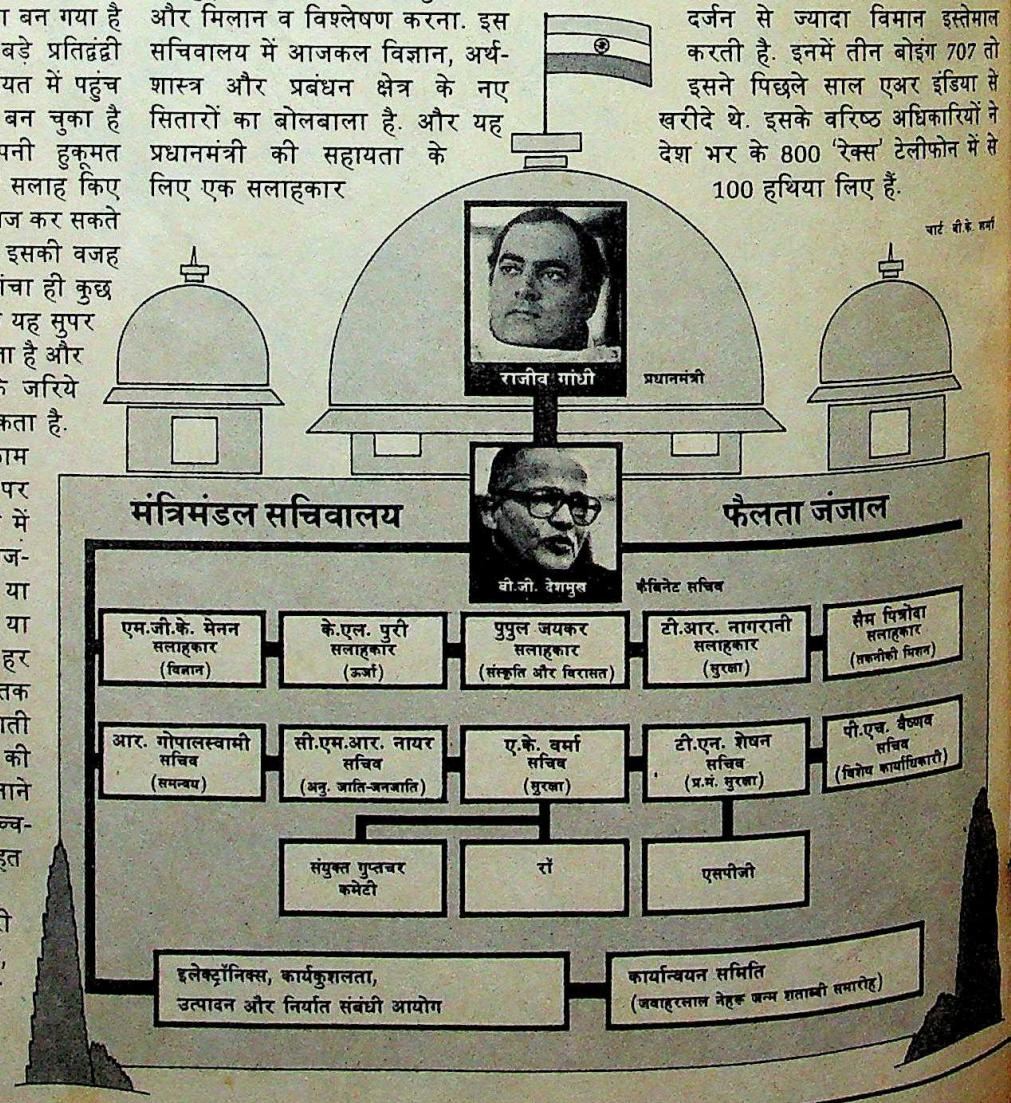

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

योजना इस सचिवालय में ऐसे 15,000 टेलीफोन लगाने की है. किसी भी दूसरे सरकारी विभाग, यहां तक कि गृह मंत्रालय को भी इतने 'रेक्स' टेलीफोन लगाने की इजाजत नहीं दी गई. इसका बजट (दूसरे मंत्रालयों से मिली अप्रत्यक्ष रकम को छोड़कर) 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है. मंत्रिमंडल सचिवालय के एक वरिष्ठ अधिकारी स्वीकारते हैं, "हम गुपचुप तरीके से अपना विस्तार कर रहे हैं.

राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद यहां सचिव स्तर के अधिकारियों की संख्या दुगुनी कर दी गई और इसे वे मामले भी सौंप दिए गए जो पहले खासतौर पर मंत्रालयों के अधीन ही रहते थे. इंदिरा गांधी के समय इस सचिवालय में सचिव स्तर के दो ही अधिकारी थे.

दिलचस्प बात तो यह है कि मंत्रिमंडल सचिवालय का आकार और दबदबा प्रधानमंत्री सचिवालय की कीमत पर बढ़ा. करीब साल भर में, दुरवाई. शारदा प्रसाद के सेवानिवृत्त होने और ओतिमा बोरदिया व गोपी अरोड़ा के तबादलों की वजह से प्रधानमंत्री सचिवालय का आकार छोटा हुआ है. खाली जगहें नहीं भरी गई. वरिष्ठ नौकरशाहों की बिरादरी यह मानती है कि प्रधानमंत्री का अपने स्टाफ को छोटा करना और अपने ही अधीन कार्यरत मंत्रिमंडल सचिवालय को ज्यादा अधिकार देना एक सोची-समझी चाल है. इसका मकसद है अपने लिए सत्ता का एक वैकल्पिक आधार तैयार करना.

मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रधान हैं महाराष्ट्र कैडर के आईएएस अधिकारी बी.जी. देशमुख, जो अपने पूर्ववर्ती प्रभातकृष्ण कौल की तुलना में कम तड़क-भड़क वाले हैं. इस कारण राजीव के साथ उनका मेल अच्छा बैठता है क्योंकि वे दबावों या प्रलोभनों के प्रति निरपेक्ष ही रहते हैं. देशमुख पहले महाराष्ट्र में मुख्य सचिव थे और अपनी ईमानदारी और कार्यकुशलता के लिए प्रसिद्ध हैं. 1986 के मध्य में वे मंत्रिमंडल सचिव बनाए गए. इसके बाद सचिव स्तर के पांच अधिकारी उनके मातहत नियुक्त कर दिए गए. ये अधिकारी हैं— टी.एन. शेषन (प्रधानमंत्री की सुरक्षा), पी.एच. वैष्णव (विशेष कार्य अधिकारी), आर. गोपालस्वामी (सचिव, समन्वय), ए.के. वर्मा (सचिव, सुरक्षा और निदेशक, रॉ), और आर.एन पालित (ओडीसा के आईपीएस अधिकारी जो आंशिक रूप से सुरक्षा का काम देखते हैं).

साफ है कि सचिवालय का दायरा काफी व्यापक है, कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहता. मिसाल के तौर पर सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक राधाकृष्ण नायर जल्द ही इस सचिवालय में अनुसूचित जाति व जनजाति कल्याण सचिव के तौर पर बहाल हो रहे हैं.

देशमुख के अलावा ज्यादातर दूसरे अधिकारी या तो राजीव गांधी के नजदीकी हैं या शासक पार्टी के असरदार सदस्यों के चेले-चपाटे. एक वरिष्ठ सरकारी अफसर के मुताबिक मंत्रिमंडल सचिवालय देश के भीतर 'नौकरशाही में राजनैतिक जवाबदेही' का प्रतीक है. टी.एन नागरानी को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक पद से रिटायर होने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री का सुरक्षा सलाहकार बना दिया गया. प्रधानमंत्री की सचिव सरला ग्रेवाल की सिफारिश पर पंजाब के पूर्व मुख्य सचिव पी.एन. वैष्णव को भी हाल ही में इस अमले में शामिल कर लिया गया. वैष्णव दो साल तक पंजाब के हालात से निबटते रहे हैं और शायद अब वहां की भावी कार्रवाईयों के लिए उनकी सेवाएं ली जाएंगी. तमिलनाडु के आईएएस अधिकारी शेषन और नायर को सचिवालय में विशेष काम सौंपा गया है. दोनों के गृह व कार्मिक राज्यमंत्री पी. चिदंबरम से अच्छे संबंध हैं. मध्य प्रदेश के सौम्य आईपीएस अधिकारी वर्मा कभी विद्याचरण शुक्ल की आंखों के तारे हुआ करते थे. जब उन्होंने शुक्ला से रिश्ते तोड़ लिए और विदेशों में सिख आतंकवादियों के खिलाफ लगातार जोरदार अभियान चलाया तो वे प्रधानमंत्री की नजरों में आ गए.

संचार और ऊर्जा के क्षेत्र में राजीव गांधी को सैम पित्रोदा और के.एल. पुरी (ऊर्जा सलाहकार) की क्षमता पर भरोसा था. उनका मानना था कि ये दोनों इन क्षेत्रों में तेजी से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं. इसलिए इन्हें भी इस सचिवालय में सचिव बना दिया. एक और अवकाशप्राप्त नौकरशाह बी.बी. वोहरा को ऊर्जा बोर्ड का अध्यक्ष मनोनीत किया गया. प्रधानमंत्री की सांस्कृतिक सलाहकार पुपुल जयकर उस पद पर इसलिए बनी हुई हैं क्योंकि वे श्रीमती गांधी की

राजीव के सलाहकार अक्सर वही काम करने लगते हैं जो विभिन्न मंत्रालयों को सौंपा गया है

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

खासमखास मित्रों में शुमार थीं.

प्रधानमंत्री को विशिष्ट सलाह देने के अलावा इस सचिवालय के अधिकारी मंत्रिमंडल द्वारा गठित विभिन्न स्थायी समितियों की भी मदद करते हैं. फिलहाल इस तरह की छह समितियां—राजनैतिक, आर्थिक, व्यय, निर्यात, समायोजन और संरचना से संबंधित—काम कर रही हैं.

मंत्रिमंडल सचिवालय की नई भूमिका में नीतियां तय करना भी शामिल है. देशमुख रोजाना आधा दर्जन से अधिक गुप्त बैठकों की अध्यक्षता करते हैं. कुछ बैठकें सचिवों के साथ होती हैं तो कुछ मंत्रियों के साथ. राजीव ने इस सचिवालय को सभी मंत्रालयों पर निगाह रखने का भी काम सौंपा हुआ है. पिछले साल राजीव ने देशमुख को एक ऐसा खाका बनाने का निर्देश दिया था जिसे देखते ही उन्हें सभी मंत्रालयों के कामकाज की ताजा स्थिति का पता चल जाए. उन्होंने सभी मंत्रालयों को समूचे वर्ष के लिए अग्रिम कार्य योजनाएं बनाने और उन्हें इस सचिवालय को सौंप देने के निर्देश भी दिए थे. वे इन रिपोर्टों से अपने मंत्रियों के कामकाज का मूल्यांकन करते थे.

प्रधानमंत्री अब इस सचिवालय के जरिये विभिन्न मंत्रालयों के फैसले भी प्रभावित करते हैं. सचिवालय ने मंत्रालयों के बीच के विवादों और मतभेदों को सुलझाने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाना भी शुरू कर दिया है. मिसाल के तौर पर, सॉफ्टवेयर निर्यातकों पर विशेष कर लगाने और उससे संबंधित रियायतें देने के मसले पर वाणिज्य और वित्त मंत्रालयों के बीच विवाद पैदा हो गया था. और इस विवाद को निबटाया देशमुख द्वारा नियुक्त सचिवों के एक दल ने.

राजीव ने पिछले साल जब सार्वजनिक क्षेत्र के घटिया कामकाज पर चिंता जताई थी तो उन्हें इसका एक कारण यह बताया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के दिन-प्रतिदिन के कामकाज में मंत्रालय जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी करते हैं. इस पर प्रधानमंत्री ने देशमुख को इसका हल ढूंढने के लिए कहा. देशमुख के सुझाव पर ही अब सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान अपने कामकाज और अपनी स्वतंत्रता और स्वायत्तता के बारे में संबद्ध मंत्रालयों के साथ सहमति पत्रों पर दस्तखत करते हैं. पेप्सी सौदा मुख्यत: इस सचिवालय के कारण ही रद्द कर दिया गया. सचिवालय ने सरकार को चेतावनी दी थी कि इस परियोजना के उलटे राजनैतिक नतीजे निकलेंगे. देशमुख मंत्रिमंडल और उसकी समितियों की सभी बैठकों के लिए कार्यसूची बनाते हैं और श्रीलंका, पंजाब पर ताजा रिपोर्ट भी देखते हैं.

सचिवालय के अधिकांश अधिकारी या तो राजीव के नजदीकी लोग हैं या फिर सत्ताधारी पार्टी के प्रभावशाली नेता उनके आका हैं

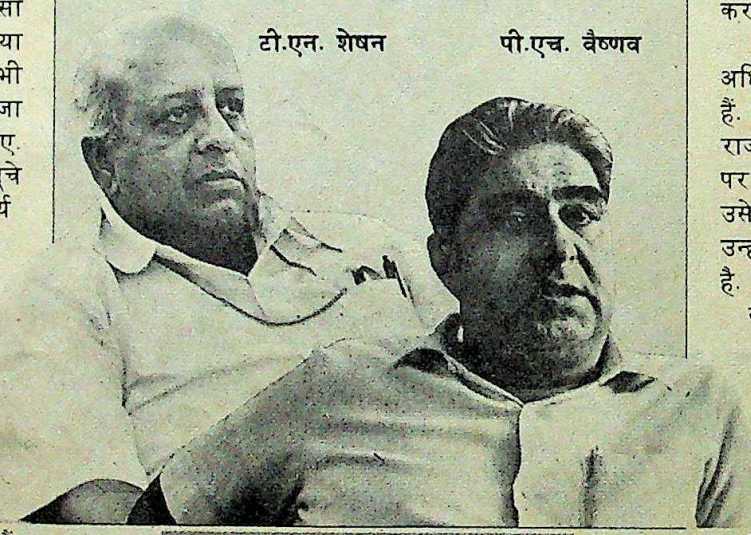

टी.एन. शेषन पी.एच. वैष्णव

सचिवालय के पांव सेना और कूटनीति के क्षेत्रों में भी पसरे हुए हैं. कूटनीति के क्षेत्र में 'रॉ' महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. इसके पहले 'रॉ' का मुख्य काम महत्वपूर्ण विदेशी सूचनाएं इकट्ठा करना भर था. श्रीलंका समझौते पर दस्तखत करने के फैसले में इसी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. तमिल छापामारों से सौदा करने में भी 'रॉ' के अधिकारी सक्रिय रहे थे.

सचिवालय के हाथ अब राज्यों और उनके स्थानीय मामलों तक पहुंच गए हैं. राजीव ने पिछले पखवाड़े जिला प्रशासन और योजना पर विचार के लिए सचिवों की एक बैठक बुलाई थी. इसकी कार्यसूची मंत्रिमंडल सचिवालय ने ही तैयार की थी. आगे की कार्रवाई का काम भी इसी संस्था के सुपुर्द कर दिया गया.

मजे की बात तो यह है कि प्रधानमंत्री के करीबी अधिकारी इस बात पर जोर देते हैं कि सचिवालय की बढ़ती भूमिका से फैसला लेने की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण हो रहा है. वे बहुत विश्वास से कहते हैं कि प्रधानमंत्री सचिवालय द्वारा फैसले करने और उन्हें मंत्रालयों पर थोपने से तो यह प्रणाली ज्यादा कारगर है. उनका तर्क है कि मंत्रिमंडल सचिवालय की इस नई व्यवस्था में प्रधानमंत्री की तरफ से काम करने वाले सचिव सभी फैसलों को प्रभावित करते हैं और उनमें मंत्रियों को शामिल करते हैं. एक वरिष्ठ सरकारी सचिव कहते हैं, "देश में मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था सही अर्थों में पहली बार काम कर रही है."

लेकिन दूसरे वरिष्ठ अधिकारी इसका खंडन करते हैं. उनका कहना है कि चूंकि राजीव नौकरशाही व्यवस्था पर भरोसा नहीं करते, लिहाजा उसे दरकिनार करने के लिए उन्होंने एक रास्ता ढूंढ़ लिया है. उनकी शिकायत है कि इस नई प्रणाली से सारी चीजें गड्डमड्ड हो रही हैं और एक-दूसरे को नीचा दिखाने की लड़ाई शुरू हो गई है. आम तौर पर मंत्रालयों द्वारा स्वतंत्र रूप से लिए गए फैसलों को मंत्रिमंडल सचिवालय की सलाह पर या तो बदल दिया जाता है या फिर उसमें बहुत ज्यादा फेरबदल कर दिया जाता है. चूंकि सचिवालय के अधिकतर अधिकारियों की प्रधानमंत्री तक सीधी पहुंच है या प्रधानमंत्री कार्यालय का उन्हें पूरा समर्थन है इसलिए वे वरिष्ठ मंत्रियों तक की बात प्राय: नहीं मानते. अधिकांश मंत्री चुपचाप यह सब देखते रहते हैं और सचिवालय के अति शक्तिशाली नौकरशाहों के सामने असहाय बने रहते हैं.

जाहिर है, जिस मकसद के लिए इस सचिवालय का विस्तार किया जा रहा है, वह कतई पूरा नहीं हो रहा है, और अगर सचिवालय पर अंकुश न लगाया गया तो इस बात की पूरी-पूरी संभावना है कि उसकी बढ़ती ताकत के कारण मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी के मूलभूत सिद्धांत की बखिया उधड़ने लगेगी.

—प्रभु चावला

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

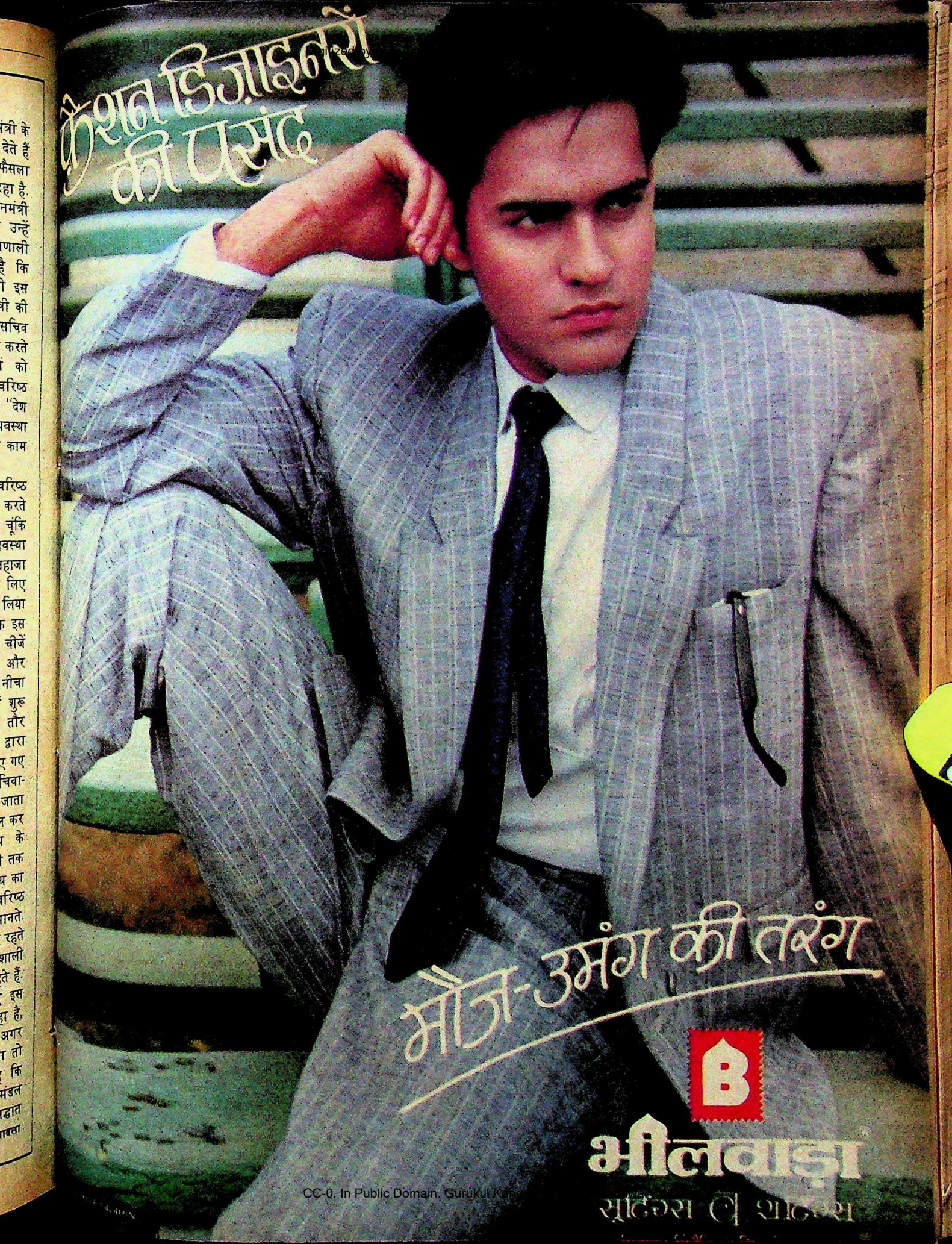

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kan

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

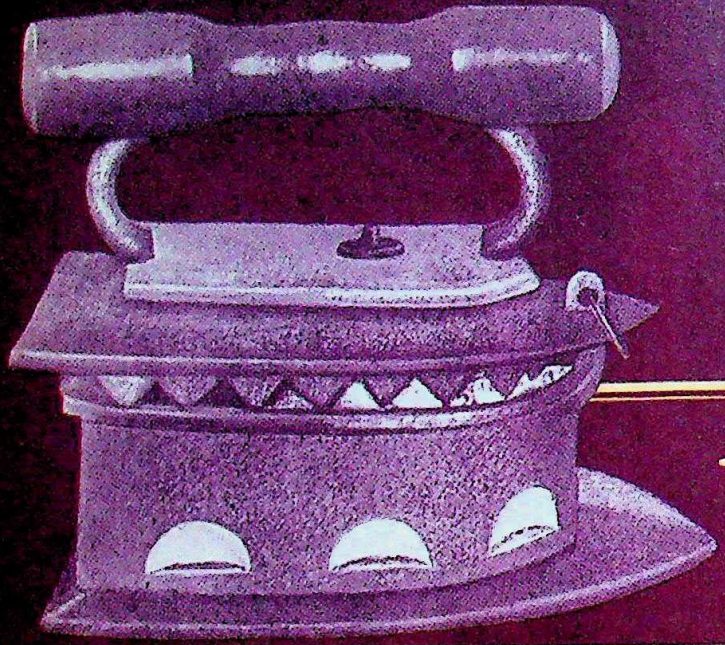

पिछले पू०स

रहन-सहन के जितभ

हम सदा आपके संग

bajaj group

बजाज स्वर्ण जयंती 1938-88

...सों में आपके ...तभी रंग बदले, ...संग रहे.

किसको विश्वास हो सकता था कि ५० वर्षों में दुनिया इतनी बदल जायेगी?

नई-नई तकनीकें. बॉल-पॉइंट पेन. क्वार्ट्ज़ घड़ियां. हृदय-प्रत्यारोपण. आकाश को छूती इमारतें. पेनीसिलीन. कंप्यूटर. विडियो. फ़ौरन चित्र देनेवाले कैमरे. ध्वनि से भी तेज़ रफ़्तारवाले यात्रा-साधन.

दुनिया कितनी आगे बढ़ती जा रही है !

बजाज इलेक्ट्रिकल्स भी सतत नवीनीकरण द्वारा दुनिया के साथ कदम मिलाकर चल रहा है. सन् १९३८ में बल्ब से जिसकी शुरुआत हुई थी, वही 'बजाज' आज देश में बिजली साधनों की सबसे विस्तृत श्रेणी प्रस्तुत करने वाली कंपनी बन गई है. इस्त्री-टोस्टर से लेकर कुकिंग रेंज और वाशिंग मशीनें ; बल्ब-ट्यूब से लेकर संपूर्ण प्रकाश संयोजना ; टेबल व सीलिंग पंखों से लेकर पूर्ण वायु-संचार व्यवस्था.

लेकिन ५० वर्षों के बाद भी हमने काम करने का कुल एक ही तरीका सीखा है–जो भी करें, बिलकुल साफ़-सही करें. अर्थात एक ऐसी कार्य संस्कृति की रचना जहां साफ़-सुथरी डिज़ाइनें, बढ़िया क्वालिटी के कलपुर्जों का उपयोग, निर्माण की आधुनिक तकनीक, क्वालिटी की सही जांच प्रणाली, और देशभर में २५०० केंद्रों के द्वारा विक्री के पहले व बाद की कुशल सेवा उसके महत्वपूर्ण अंग हैं.

bajaj बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
जैसी कथनी वैसी करनी

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पप्पी संस्कृति

पैसे से प्रतिष्ठा पाने की सनक

पंजाबियों की परंपरा अब दूसरे नव-धनाढ्य तबकों में भी फैल रही है

पश्चिमी देशों में युवा शहरी व्यवसायियों की नई मनमौजी जमात उभरने लगी तो उसे बाकायदा 'यप्पी' नाम दिया गया. इनकी ही बिरादरी अब बंबई जैसे महानगरों में भी पैदा होने लगी है. दिल्ली में इसे 'पप्पी' नाम देकर शब्दकोश में खासा इजाफा किया गया है. 'पप्पी' यप्पी की ही तर्ज पर गढ़ा गया शब्द है. 'पप्पी' का 'प' पंजाबी बिरादरी के लिए रखा गया है. ये लोग शहर के समृद्ध युवा पंजाबी हैं. दिल्ली की नव धनाढ्य पंजाबी संस्कृति के ये प्रतीक तड़क-भड़क के शौकीन, रुतबे के प्रति सतर्क और हद दर्जे के धनलोलुप हैं. इन लोगों के बारे में अब चुटकुले भी प्रचलित हो गए हैं. कुछ बानगियां देखें: अरे भाई! पप्पी बढ़िया शादी कौन-सी मानते हैं? शादी करवाते हैं वे वीडियो से, और दहेज में मांगते हैं दुलहन. हां, तो ये खाते-पीते क्या हैं? आलू का परांठा, गाजर का हलवा और ऊपर से ठंडा कोला लाइट. और उनकी बेहतरीन शामें कैसे गुजरती हैं? स्कॉच में मदहोश होकर गुलाम अली की गजलें सुनते हुए.

और स्कॉच भी केवल ब्लैक लेबल, उससे कम नहीं. घर वातानुकूलित, कार और कपड़े खास तौर पर विदेशी, आचार-व्यवहार में तड़क-भड़क और अकड़ तथा दौलत इतनी कि सारा जग देखे. ये जो कुछ भी करते हैं, दूसरों पर प्रभाव जमाने के लिए. बड़े-बड़े लोगों के साथ अपने संपर्क जताना और लोगों को अपनी तरफ अनायास आकर्षित करना उन्हें भाता है. उनके लिए इस बात का ज्यादा महत्व नहीं कि वे क्या करते हैं. महत्वपूर्ण यह है कि वे किसी काम को किस तरह और कहां अंजाम देते हैं. उनके आयोजन भी एकदम नए पांच सितारा होटलों में होते हैं.

यह वर्ग तुरत-फुरत कमाए गए पैसे के बल पर जिंदगी में गुलछर्रे उड़ाता है. उसकी आडंबरपूर्ण जीवन शैली काले धन से सराबोर है. पैसा ही उसका माई-बाप है और उसी के जरिये वह प्रतिष्ठा हासिल करता है. ज्यादा पैसा होने पर भी इसकी पसंद का स्तर उतना ऊंचा नहीं. इसका इस्तेमाल वह महंगी और बड़े नाम वाली चीजें खरीदकर वाहवाही कमाने में करता है. लिहाजा, वह काले बाजार की स्कॉच खरीदने पर ही जोर देता है, भले ही उसे अमूमन ब्लैक लेबल और ब्लैक नाइट में कोई फर्क भी न पता हो. दिल्ली में बड़े पैमाने पर गैरकानूनी शराब का धंधा करने वाले एक व्यक्ति के मुताबिक, "स्कॉटलैंड में जितनी ब्लैक लेबल बनती है, उससे कहीं ज्यादा दिल्ली में (गैर-कानूनी तरीके से) बिकती है." राजधानी में ऐसी ह्विस्की की प्यास का भरपूर फायदा उठाकर यह व्यक्ति भी नवधनाढ्य वर्ग में शामिल हुआ है. उसका कहना है, "दिल्ली में बिक रही 70 फीसदी स्कॉच नकली है."

तड़क-भड़क के शौकीन, रुतबे के प्रति सतर्क और धनलोलुप इन लोगों का माई-बाप पैसा ही है और उसी से ये प्रतिष्ठा खरीदते हैं

जिस तरीके से पप्पी पैसा उड़ाते हैं, उसके लिए उन्हें धूर्त हरगिज नहीं करार दिया जा सकता. उनका मकसद तो पैसा दिखाकर लोगों पर अपना रौब जमाना है. अनुभवी पप्पी की चाल-ढाल और आचार-व्यवहार नौसिखिए से अलग होता है. अनुभवी पप्पी किसी रेस्तरां में घुसते ही काउंटर पर सौ के नोटों की गड्डी लहरा देता है ताकि वहां उसकी विशेष रूप से आवभगत हो.

पप्पी की पहचान के लक्षण क्या हैं? कई बरस तक पप्पी वर्ग की वेशभूषा सफारी सूट (जिसे सुपारी सूट भी कहते हैं) रही. लेकिन अब इसे नए पप्पी ही पहनते हैं. किसी व्यक्ति के पैरों में सफेद सैंडल हो, हाथ में क्लासिक सिगरेट का पैकेट और एक कीमती लाइटर हो और उंगुलियों में कई अंगूठियां हों तो समझ लीजिए वह नव दीक्षित पप्पी ही है. बंबई से दिल्ली आने वाले 'माढू' (मारवाड़ी) और 'गुज्जु' (गुजराती) किस्म के पप्पी अभी भी यही पोशाक पहनते हैं लेकिन उनके हाथ में सिगरेट के पैकेट की जगह पान बहार का डिब्बा और माथे पर धूप का कीमती चश्मा चढ़ा होता है.

विदेशों की यात्रा कर चुके अनुभवी पप्पी या तो आयातित वस्त्र पहनते हैं या फिर बहुत ही महंगे

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Haridwar.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सभी कार्टून: अजीत नाइनन

देसी कपड़े. साथ ही गले में सोने की मोटी जंजीर, सोने का कंगन और सोने की घड़ी होना भी जरूरी है. नाभि तक खुली हुई शर्ट, सफेद पैंट और सफेद सैंडल तो सभी प्रकार के पप्पियों की आम पसंद है.

पप्पी को हालांकि हर 'इंपोर्टेड' (आयातित) चीज— कार, मखमली गद्दे और सौंदर्य प्रसाधन के प्रति सनक रहती है पर उसका खाना देसी होता है. उसका खाना बटर चिकन और शाही पनीर के बगैर पूरा ही नहीं होता. और उसके लिए 'चाइनीज़ फूड' का मतलब है पहले स्वीट कॉर्न चिकन सूप और फिर चिली चिकन का स्वाद लेना. अगर कोई जरा साहसी हुआ तो वह हॉट-पॉट सूप और लहसुन वाले चिकन के अलावा कुछ नहीं खाएगा. विदेश हो आए पप्पी की तो पूछिए ही मत. उसकी बीवी भी शायद उसे 'डी-जे' (डार्लिंग जी) कहकर बुलाए.

इस संस्कृति को हालांकि पंजाबियों ने शुरू किया पर अब यह बनियों, मारवाड़ियों और दिल्ली में पिछले दो दशक की सुनहरी अवधि के पैसा बनाने वाले दूसरे समुदायों में भी लोकप्रिय हो रही है. वही समय था जब फल-फूल रहे नए कारोबार में दर्जनों वस्त्र निर्यातक, इलेक्ट्रॉनिक और टीवी डीलर, हथियार विक्रेता, लॉटरी वाले, भवन और शराब के ठेकेदार, लकड़ी के व्यापारी, अचल संपत्ति के एजेंट, रेस्तरां और होटल मालिक, मोटर के कल-पुर्जों के व्यापारी तथा वकील और डॉक्टर करोड़पति बने.

दूसरे शहरों में भी इसी तरह की संस्कृति परवान चढ़ रही है. बंगलूर के सिंधी, बंबई के फिल्मी सितारे और हैदराबाद के तंबाकू के बड़े व्यापारी पानी की तरह बरसते पैसे को पानी की तरह ही बहा रहे हैं. पप्पी का शुरुआती प्रतीक मारुति कार है जिस पर जगह-जगह स्टिकर लगे होते हैं. अगल-बगल के शीशों पर चटकीले रंग के धारीदार कपड़े लटके रहते हैं और उसमें इस तरह का हॉर्न लगा रहता है जो हर मौसम में संगीतमय धुन बिखेरता है. उसकी मारुति के शीशे निश्चित रूप से गाढ़े रंग के होते हैं. गाड़ी के डैशबोर्ड पर एक छोटा टीवी सेट और छत पर गश्ती फोन का एंटीना भी लगा रहता है, भले ही कार में फोन का नामोनिशान भी न हो. पिछले शीशे पर 'यह राजिंदर की कार है' जैसा कोई एक अर्थहीन वाक्य भी चिपका रहता है. कुछ साल पहले तो 'बंटी ते पिंकी दे पापा दी गड्डी' जैसा वाक्य भी लिखा रहता था. पप्पी तबके में पहुंचने के लिए आयातित कार तो चाहिए ही, भले ही वह टोयोटा, गोल्फ या इसुजु ही क्यों न हो. 'निर्वाण' पाने के लिए मर्सिडीज भी ठीक है लेकिन पप्पी बड़ी खुशी से मर्सिडीज के तिकोने को पांच (कोने वाले) तारे में बदल देगा.

भौगोलिक मायनों में इस विकास का अर्थ है चांदनी चौक या चावड़ी बाजार या करोलबाग या राजेंद्र नगर से दक्षिण दिल्ली की अपेक्षाकृत नई कॉलोनियों में जा बसना. पप्पी यहां या तो कोई आलीशान मकान खरीदता है या बनवाता है. ऐसे घरों में संगमरमर और धौलपुरी पत्थर लगे रहते हैं, हर कमरे में पूरे आकार के विभिन्न रंगों के कालीन बिछे होते हैं, मखमली गद्दों वाला नक्काशीदार फर्नीचर होता है, झाड़-फानूस लटके रहते हैं और पप्पी की विदेश यात्रा के सबूत के तौर पर कुछ नायाब चीजों का संग्रह होता है. लेकिन आम तौर पर इस घर का बाथरूम और किचन गंदा रहता है.

पप्पी जगत का कई तरह का आकार-प्रकार होता है. गुड़गांव के उस सज्जन को ही लीजिए जो जमीन की खरीद-फरोख्त करता है और अपना हर दिन एक पांच सितारा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आपके दोस्त जब आपसे कैरीबिअन के रिसॉर्टों की बात करें, तो आप उन्हें गोआ के खूबसूरत डालमिया रिसॉर्ट के बारे में बताइए

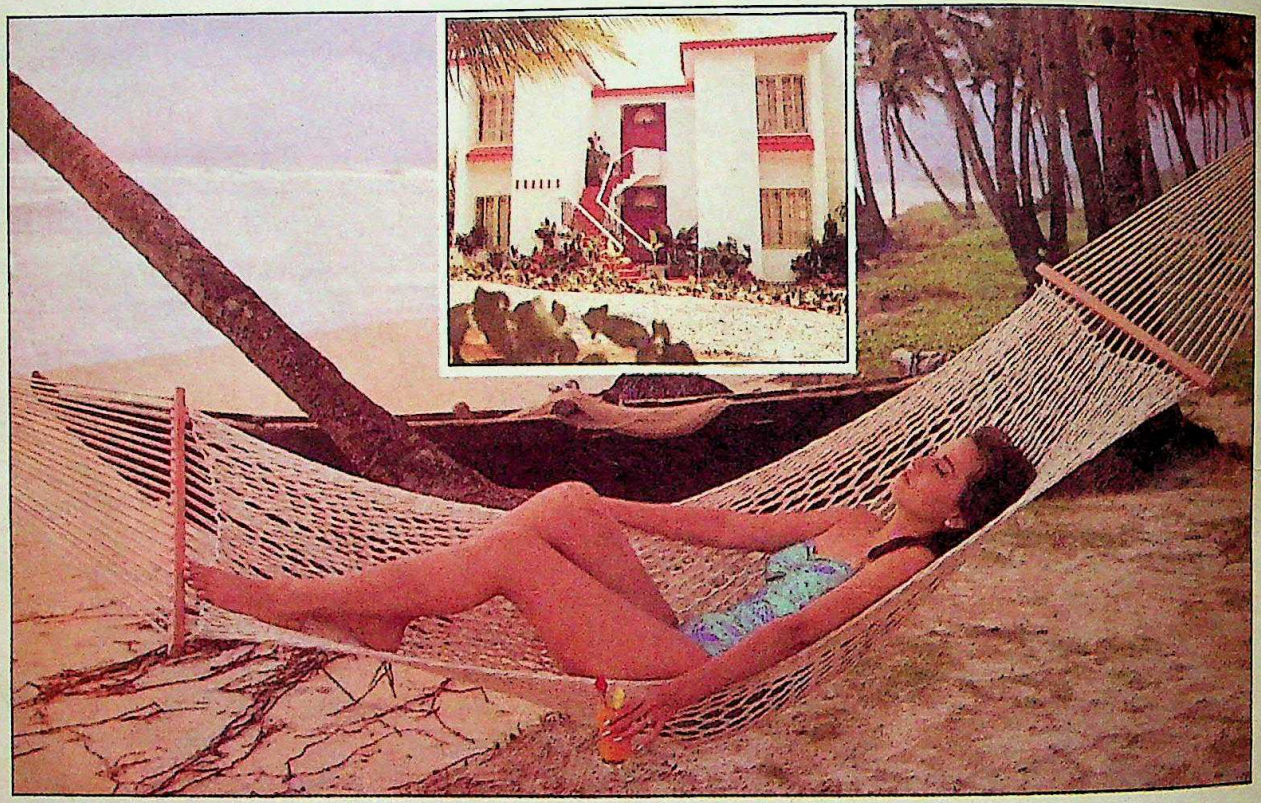

द ओल्ड ऐंकर

कवेलोसिम बीच पर, एक ओर अरब सागर और दूसरी ओर साल नदी। 200 रिहायशी यूनिट - एयरकंडीशंड और पूरी तरह फर्निश्ड, लिनेन, क्राकरी और कटलरी सभी कुछ मौजूद। और साथ में पूरी तरह सुसज्जित रसोई।

द ओल्ड ऐंकर जल्द रहने के लिए तैयार हो जायेगा आपके आनंद के लिए, हमेशा आपके पास।

लक्ज़री रिसॉर्ट की सुविधाएं—जीवन भर आपके साथ

* स्विमिंग पूल * हेल्थ क्लब * रेस्टारैंट * बार * फूड प्लाजा * अनेक वाटर स्पोर्ट्स * टेनिस * सम्मेलन की सुविधाएं। इसके अलावा भी बहुत कुछ।

वैकेशन ओनरशिप —एक उत्तम योजना

वैकेशन ओनरशिप में, आप रिसॉर्ट में एक यूनिट हर साल एक निश्चित सप्ताह या सप्ताहों के लिए उपयोग करने का अधिकार खरीद लेते हैं।

वैकेशन ओनरशिप—अनेक बड़े फ़ायदे

* आपके छुट्टियां मनाने पर बढ़ती कीमतों का असर नहीं पड़ेगा।
* आप अपने यूनिट सप्ताह/सप्ताहों को बेच सकते हैं। किराए पर या किसी को उपयोग के लिए दे सकते हैं। उपहार में दे सकते हैं। या वसीयत में दे सकते हैं — जिसे चाहें उसे।
* आपकी वैकेशन ओनरशिप हमेशा कायम रहेगी।

लागत की बात

कीमतें सीज़न और यूनिट टाइप के अनुसार रु. **13,500** से ले कर रु. **28,500** तक हैं। साथ में मामूली रखरखाव डिपाज़िट। और यदि ज़रूरी हुआ तो वार्षिक रखरखाव के लिए थोड़ी फ़ीस।

भुगतान के लिए किश्त योजना भी है जिसमें अभी तक का तुरंत भुगतान रु. **4,200** से लेकर रु. **11,900** तक है।

रिसॉर्ट की कुछ सुविधाएं पैसा देकर होंगी और कुछ बिना किसी अतिरिक्त लागत के मिलेंगी।

आज गोआ, कल सारी दुनिया

आप गोआ के अपने यूनिट सप्ताह/सप्ताहों को भारत भर में बनने वाले किसी डालमिया रिसॉर्ट से बदल सकते हैं। **रिसॉर्ट कंडोमिनिअम्स इंटरनेशनल (आर.सी.आई.®)*** से संबंध के ज़रिए आप अपने यूनिट सप्ताह (सप्ताहों) को विश्व भर में फैले **1,300** रिसॉर्टों से बदल सकते हैं—यदि दूसरी जगह में यूनिट सप्ताह उपलब्ध हों तो, इसके लिए **आर.सी.आई.®** को मामूली एक्सचेंज फीस देनी होगी।

द ओल्ड ऐंकर, गोआ। आप के लिए आनंद, हमेशा के लिए।

*** रिजर्व बैंक आफ इंडिया की मंजूरी मिलने पर।**

कृपया द ओल्ड ऐंकर रिसॉर्ट, गोआ के बारे में पूरा ब्यौरा मेरे पास भेजिए।
मैं समझता हूं कि यह ब्यौरा मुफ्त होगा और इससे मेरे ऊपर खरीदने की कोई बंदिश नहीं होगी।

नाम _____

पता _____

_____

_____

टेलीफोन: आफिस _____ घर _____

DALMIA RESORTS International

the Old Anchor
A DALMIA RESORT

डालमिया रिसॉर्ट्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड

पहली मंजिल, देविका टावर,
6 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019
फोन 6441554, 6445971, 6414113
टेलेक्स: 031-71095 DRI IN

किश्त योजना का लाभ लीजिए

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

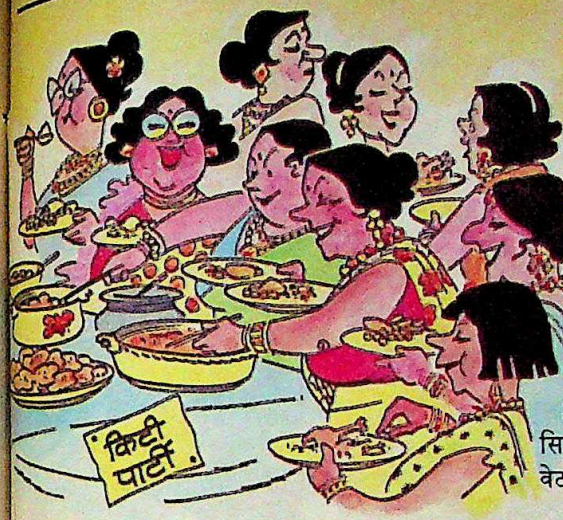

होटल के बार में बिताता है. वह रोज सुबह 11 बजे वहां पहुंच जाता है और खाने के समय को छोड़कर रात 11 बजे तक लगातार (निश्चित रूप से स्कॉच ही) पीता रहता है. उसी बार में प्रायः जाने वाले एक दूसरे व्यवसायी का कहना है, "वह जमीन-जायदाद का धंधा करता है और दिन के खत्म होने पर ही उस पर असल शबाब चढ़ता है."

या उस डेयरी मालिक की मिसाल लीजिए जो दक्षिण दिल्ली के एक विशेष रेस्तरां में व्यवसायियों के एक नए ग्रुप को खाना खिलाने लाता है. वह शैंपेन के लिए वेटर को हर बार 1,000 रु. थमाता है और यह घोषणा करने का निर्देश देता है कि ये रुपए प्रबंधक की शुभकामनाओं सहित दिए जा रहे हैं. ऐसी ही एक पार्टी में उसने 30 लोगों के खाने का आदेश दिया लेकिन आए 14 ही. वहां वेटरों को उसने 2,500 रु. बख्शीश दी और सलाम बजाने के लिए लाइन में खड़े दूसरे कर्मचारियों को भी 3,000 रुपए दिए. वह पान या सिगरेट का एक पैकेट लाने के लिए वेटरों को 100 रु. टिप देता है.

दुकानदार भी महसूस करते हैं कि ऊंचे दाम वाली पर्ची लगा देने से मालदार ग्राहकों के आने की संभावना अधिक रहती है. इंटरशॉप समूह के मालिक विजय मेहता मानते हैं कि पुरुषों के लिए नई खोली गई विशेष इंटरमेज्जो-लाइनिया शॉप में डिजाइनदार वस्त्रों की कीमत 'बहुत ही अधिक' है. पर ऐसा वे जानबूझकर करते हैं. उन्हें पता है कि पप्पी अपने वर्ग के हिसाब से कीमत को देखता है और यदि उसी कपड़े की कम कीमत रखी जाए तो वह उसे नहीं खरीदेगा. लाइनिया शॉप की प्रबंधक नैंसी चोपड़ा का कहना है, "हमारी दुकान में तो ऐसे लोग आते हैं जिनकी जेबें पैसों से भरी होती हैं."

पश्चिम का 'यप्पी' जहां स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहता है, वहीं इसके विपरीत यहां के पप्पी को अपना खान-पान बेहद पसंद है और वह अपनी इस पसंद को बढ़ा-चढ़ाकर प्रदर्शित भी करता है. पांच सितारा होटल के एक हेल्थ क्लब में हर रविवार को जाने वाले पप्पी उद्योगपतियों के एक ग्रुप ने स्वास्थ्य बनाने के बजाय वहां शराब पीना शुरू कर दिया. इस पर होटल के प्रबंधकों ने उन्हें एक कमरा दे दिया जिसमें वे मौज-मस्ती करते और शराब पीते बिताते हैं.

इसलिए कोई ताज्जुब नहीं कि पप्पी अपनी कार को मयखाने के रूप में और इंडियन एअरलाइंस को 'लास्ट चांस सैलून' के रूप में इस्तेमाल करना पसंद करते हैं. दिल्ली के पप्पी चलती या खड़ी कार में शराब पीते हैं जबकि बंबई के पप्पी दिल्ली-बंबई उड़ान में पीते हैं. विमान उड़ने के बाद सच्चे पप्पी की पहचान तुरंत उसके हाव-भाव से हो जाती है. वह विमान परिचारिका से एक गिलास और कुछ बर्फ मांगेगा. फिर छोटी बोतल में रखी शराब निकालेगा और पिएगा.

कार को चलता-फिरता मयखाना बनाने के लिए फर्नीचर निर्माता को दाद देनी चाहिए जो कार के डैशबोर्ड में ऐसी कारीगरी कर देता है कि उसमें लगी टोंटी के नीचे गिलास कीजिए, व्हिस्की का लुत्फ उठाइए.

दिल्ली पप्पी जगत का मक्का है. यहां अमृतसर, लुधियाना, श्रीनगर और फरीदाबाद सरीखे आसपास के शहरों से पप्पी अक्सर आते हैं और दिल्ली के अपने धर्म बंधुओं को मात देने की कोशिश करते हैं. पंजाब के एक शहर के उस होटल मालिक को ही लीजिए जो अपने दोस्तों के एक ग्रुप को खाना खिलाने और गजल सुनवाने के लिए दिल्ली के पांच सितारा होटल के एक भारतीय रेस्तरां में प्रायः लाता रहता है. ग्रुप का हर सदस्य एक-एक बोतल स्कॉच

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पीता है और पंजाबी मेजबान हर तीन-चार पैग के बाद नशा कम करने के लिए लस्सी पीता है. और जब शाम ढलती है और मन में तरंगें हिलोरें लेने लगती हैं तो वे 100-100 के नोटों के साथ गजल गायक के पास अपनी फरमाइशें भेजना शुरू करते हैं. एक चश्मदीद के मुताबिक पिछले साल इसी तरह की एक लंबी शाम के दौरान नशे में धुत्त इस होटल मालिक ने गजल गायक को 37,000 रु. दे डाले थे. एक साल में तीन मौकों पर उसने उस गजल गायक पर 10,000 से भी अधिक रुपयों की वर्षा कर डाली.

इसी तरह पास के कस्बे के एक शराब ठेकेदार ने अपने बेटे की सगाई के मौके पर एक दूसरे पांच सितारा होटल में शैंपेन की नदी बहा दी. उसने 100 बोतल शैंपेन लाने का आदेश दिया था. हर बोतल की कीमत 1,000 रु. थी. 18 बोतल शैंपेन तो सगाई वाले जोड़े के सिरों पर उड़ेल दी गई. इस शैंपेन स्नान के बाद ही बाकी बची शराब मेहमानों के बीच परोसी गई.

बड़े आदमी के रूप में खुद को प्रतिष्ठित करने के इच्छुक लुधियाना के एक फिजूल-खर्च उद्योगपति ने एक बार दिल्ली के एक डिस्कोथे में हर आदमी को शराब परोसने की जिद की. डिस्कोथे में जब शैंपेन खत्म हो गई तो उसने मौज-मस्ती मारने वाले अधिकतर लोगों को अपने कमरे में ही आने का न्यौता दे डाला और पास के एक होटल से दो क्रेट शैंपेन मंगवा ली. दूसरे दिन उसने किराए पर एक वातानुकूलित बस ली और सभी लोगों को आगरा घुमाने ले गया.

अपनी शानोशौकत और तड़क-भड़क दिखाने के लिए पप्पी कल्पना की लंबी उड़ानें भरते हैं. शादियों पर तो वे बेशुमार पैसे खर्च करते हैं. दिल्ली के उस स्थूलकाय भद्र पुरुष की ही मिसाल लीजिए जो 4 जुलाई को पोटामक नदी पर होने वाली आतिशबाजी देखने के लिए किसी को वाशिंगटन भेजना चाहता था. उसका मकसद अपनी लड़की की शादी में भी उसी तरह की आतिशबाजी की व्यवस्था करना था.

धन-दौलत और कल्पनालोक गढ़ने की चाह ने शादी के मेहमानों को भी 'अरेबियन नाइट्स' के प्रति आकर्षित किया है. हाल ही में दक्षिण दिल्ली के एक होटल ने एक ठेकेदार के लड़के की शादी के लिए गत्ते और बालू के मॉडलों से अलिफ लैला के दृश्यों का पुनर्निर्माण कर दिया था. परिवार के सदस्य और मेहमान 'अरब के सरदारों' के भेष में आए और पीले साटिन की वर्दी पहने बैरे हॉलीवुड के शेखों की तरह मेहमानों की खातिरदारी करते रहे. इतना ही नहीं, माहौल पूरी तरह से अरेबियन नाइट जैसा बनाने के लिए मिस्र से एक चुस्त-दुरुस्त बैले नर्तकी करीना को भी बुलाया गया.

'पप्पी' लोगों का एक दूसरा महत्वपूर्ण शगल है किटी पार्टी. यह पार्टी पप्पी बालाओं या महिलाओं की होती है. वे एक जगह इकट्ठा होकर अपने-अपने नखरे दिखाती हैं और चली जाती हैं. हर किटी पार्टी के पहले व्यापक तैयारियां की जाती हैं. पप्पी महिलाएं अपने चेहरे सजाने-संवारने के लिए ब्यूटी पार्लर में जाती हैं. अपने बाल ठीक करवाती हैं और आधुनिक कपड़े खरीदती हैं.

उस पप्पी औरत का तो भगवान ही मालिक है जो ऐसा परिधान पहने होती है जिन्हें दूसरी पप्पी स्त्रियां पहले ही देख चुकी हैं. उस पर छूटते व्यंग्यबाणों की एक बानगी देखिए. "क्या शानदार लिबास है, भई! उस पार्टी में भी तुमने यही नहीं पहन रखा था?" चारों ओर कीमती नगों और सोने की चमक तथा विभिन्न इत्रों की महक. यहां बातचीत का दायरा भारी कटाक्ष से लेकर घिसी-पिटी चीजों तक होता है. किटी पार्टी का सदस्य होने के लिए 500 से लेकर 1,000 रु. तक चंदा देना पड़ता है. कुछ महिलाएं तो एक साथ पांच किटी पार्टियों की सदस्य होती हैं. कभी-कभी विजेता 25 हजार रु. तक बटोर लेती है.

सभी पप्पियों के मन में इच्छा रहती है कि उन्हें समाज में सबसे बड़ा आदमी माना जाए. और वे अपने पैसे के बूते पर इसके लिए कोशिश करते रहते हैं. कई तो इसमें सफल हो जाते हैं. बाकी समय बीतने के साथ-साथ सौम्य बन जाते हैं और बुढ़ापे में पहुंचकर आराम से जिंदगी गुजारते हैं.

—रमिंदर सिंह

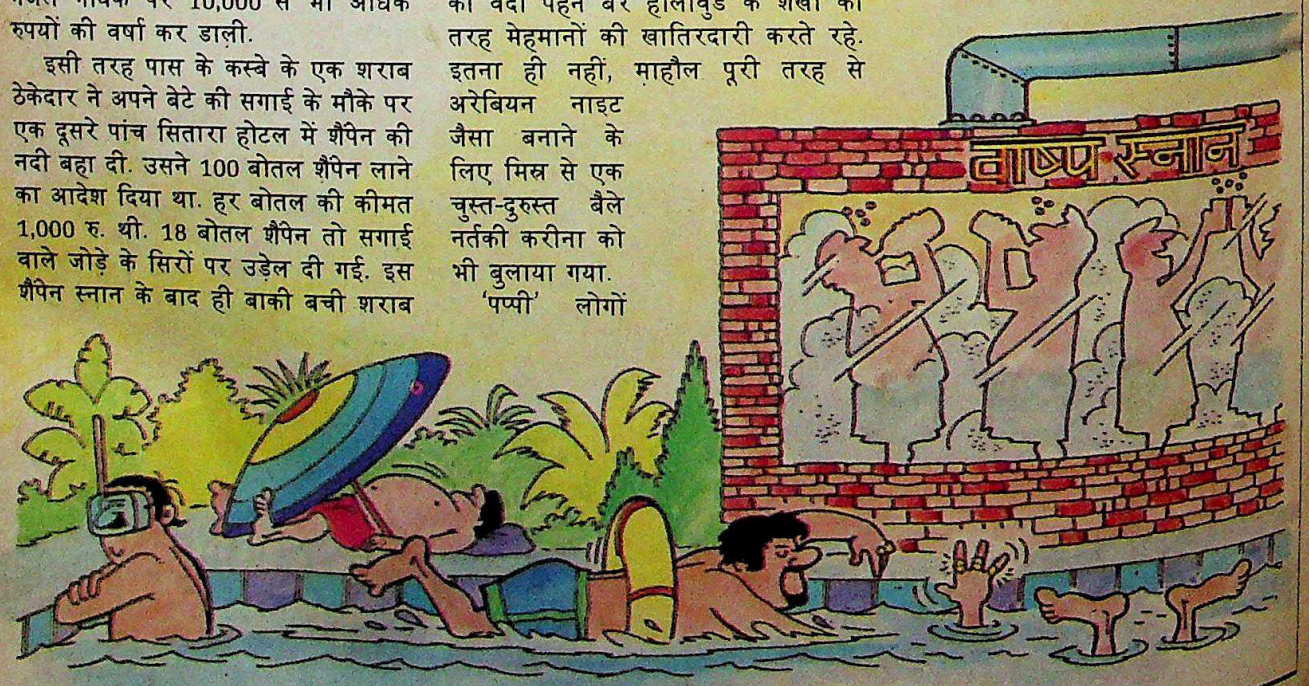

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अशोक ग्रुप के सप्ताहांत पैकेज से जिंदगी की भागदौड़ को भूल जाइये.

रोमांच, मनोरंजन, आराम और मौज-मस्ती – इन सबको है आप का इंतजार। सप्ताहांत के दिनों को खूबसूरत बनाने के लिए तैयार हो जाइए – अशोक ग्रुप की सैर सपाटे की एकमुश्त योजना की मदद से। खर्च मात्र प्रति व्यक्ति प्रति रात रु. 125* आएगा।

यह योजना दंपत्तियों, परिवारों तथा ग्रुपों के लिए आदर्श है। 12 वर्ष से कम आयु के दो बच्चों के रहने का खर्च निःशुल्क (बिना अतिरिक्त बिस्तर के)।

हमारे रेस्टोरेण्ट में आपको स्वाद और परिवेश का शानदार संगम मिलेगा। सप्ताहांत बिताते हुए शानदार व्यंजनों का स्वाद लीजिए।

मीनू कार्ड पर लिखे दामों पर 10% की विशेष छूट।

शुक्रवार रात्रि 8 बजे आइये और सोमवार प्रातः 8 बजे तक ठहरिये। 15 अप्रैल से 31 अक्तूबर '88 के बीच किसी भी सप्ताहांत में इस अवसर का लाभ उठाइये।

* सभी कर अतिरिक्त

The Ashok Group
HOTELS • TRAVEL SERVICES • DUTY FREE SHOPS

India Tourism Development Corporation

यह योजना निम्नांकित अशोक ग्रुप होटलों में उपलब्ध है:

• आगरा अशोक • औरंगाबाद अशोक • होटल अशोक, बंगलौर • भरतपुर फारेस्ट लॉज • कलिंगा अशोक, भुवनेश्वर • अशोक ट्रैवलर्स लॉज, बोधगया • एयरपोर्ट अशोक, कलकत्ता • हसन अशोक, • जयपुर अशोक • जम्मू अशोक • खजराहो अशोक • कोवलम अशोक बीच रिसोर्ट • मदुरै अशोक • टेम्पल बे अशोक बीच रिसोर्ट • ममल्लापुरम • ललिता महल पैलेस होटल, मैसूर • लोधी होटल • होटल रंजीत (विशुद्ध शाकाहारी), नयी दिल्ली • पाटलिपुत्र अशोक, पटना • वाराणसी अशोक

जानकारी और बुकिंग के लिए किसी भी अशोक ग्रुप होटल या अशोक नेटवर्क सर्विस के इन केन्द्रों से संपर्क करें – बम्बई (फोन: 2026481, 2026022); कलकत्ता (फोन: 435208, 435264); दिल्ली (फोन: 600121); मद्रास (फोन : 473078, 472186) बंगलौर (फोन: 79411, 73494)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारत-पाक रिश्ते

पल में तोला, पल में माशा

गंभीर आरोपों की तीखी बौछार से फिर लड़ाई का अंदेशा

आतंकवादियों को पाकिस्तानी मदद के सवाल पर भारत में जिस तरह आरोपों की झड़ी लगी उसे देखते हुए एक बार तो ऐसा लगा मानो दोनों पड़ोसी फिर से लड़ाई में उलझने जा रहे हैं. पर फिर अचानक ही संबंधों में मधुरता के बोल सुनाई पड़ने लगे. इस गरमा-गरमी के बारे में वरिष्ठ संवाददाता ***रमिंदर सिंह*** *का खोज भरा विश्लेषण:*

तनाव बहुत सोच-समझकर भड़काया गया. पाकिस्तान पर पंजाब के आतंकवादियों की मदद करने और उन्हें उकसाने के आरोपों के सुर धीरे-धीरे तार सप्तक में बदलते गए. इस वाद्य-वृंद का संचालन और कोई नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री राजीव गांधी कर रहे थे. उन्होंने संसद और बाहर यही सुर फूंकने का जिम्मा अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों—बूटा सिंह, कृष्णचंद्र पंत और नटवर सिंह को सौंप रखा था. इन तीनों की एकल प्रस्तुतियां भी कम कर्णकटु नहीं रहीं. राजीव ने तो पाकिस्तानी सदर जिया-उल-हक को संकटों से घिरे पंजाब में टांग न अड़ाने की सख्त चेतावनी दे दी. बूटा सिंह उनसे भी आगे बढ़ गए. कूटनीतिक भद्रता को ताक पर रखकर उन्होंने जिया के इनकार को 'झूठ का पुलिंदा' करार दे डाला. और सियाचिन की बर्फीली पहाड़ियों में लगातार गूंज रहे धमाकों के बीच लगने लगा कि दोनों मुल्क सशस्त्र संघर्ष की दहलीज पर फिर खतरनाक ढंग से आस्तीनें चढ़ाने लगे हैं.

लेकिन तनाव का पारा जिस तेजी से चढ़ा उसी फुर्ती से नीचे भी आ गया. पिछले पखवाड़े सुलह-सफाई के लिए भारत ने विदेश सचिव के.पी.एस. मेनन को इस्लामाबाद भेजा. वहां वे राष्ट्रपति जिया और विदेशमंत्री जैन नूरानी से मिले. इसके साथ ही दोनों देशों ने अपने गृह सचिवों और रक्षा सचिवों की रुकी हुई बैठकें फिर से शुरू करने की घोषणा की.

लेकिन मार्च शुरू होते ही संयत भाषा को तिलांजलि दे दी गई. केंद्रीय मंत्रियों और पंजाब के राज्यपाल सिद्धार्थशंकर राय ने पाकिस्तान पर आरोप मढ़ा कि वह आतंकवादियों के शस्त्रागार में एके-47 स्वचालित राइफलों और रॉकेटों जैसे घातक और नए हथियारों की बढ़ोतरी करके पंजाब में दखलदाजी बढ़ा रहा है. पंजाब में कुछ रॉकेट मिलने, जूझारू अकाली नेता जीवन सिंह उमरानंगल तथा एक पुलिस दल पर रॉकेटों के हमले से सरकार को 59वां संविधान संशोधन विधेयक पास करवाने के लिए संसद पर दबाव डालने का मौका मिल गया. इस संशोधन से सरकार पंजाब में आंतरिक इमरजेंसी लगाने के अधिकार से लैस हो गई है. लोकसभा ने यह संशोधन 23 मार्च को पास किया और एक हफ्ते के अंदर ही राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर उसे कानून का रूप दे दिया.

पंजाब में दखलंदाजी के सवाल पर भारतीय आरोप पत्र

about Pakistan's assistance to Sikh terrorists. On different occasions, both in writing and verbally, information has been conveyed to the Government of Pakistan.

2. A numbe[illegible]

Atinder Pal Sin[illegible]

the information in question is acknowledged to be based on confessions obtained from persons under police detention. Secondly, the persons involved seem to be smugglers, traffickers, criminals and other persons of questionable antecedents who would have scant regard for truth and much less for Pakistan-India relations. Such persons, parti[illegible]

[illegible] the contrary, there is incontrovertible evidence that Pakistan continues to aid and abet extremist activities directed against India.

As indicated on several earlier occasions, Pakistan's involvement with anti-Indian secessionist activities extends to:

permitting its territory as sanctuary for extremist Sikh elements and as a base for training and indoctrination;

supply of arms and ammunition to Sikh secessionist

वाक्युद्ध अप्रैल में भी जारी रहा. अप्रैल के पहले हफ्ते में दौरे पर आए अमेरिकी रक्षा सचिव फ्रैंक कार्लूसी से राजीव ने कहा कि वे जिया को पंजाब में अपनी कारगुजारियां बंद करने के लिए कहें. हालत तब और बदतर हो गई जब कार्लूसी ने पाकिस्तान पहुंचकर घोषणा कर डाली कि अफगानिस्तान से रूसी सेनाओं की वापसी के बाद भी अमेरिका पाकिस्तान को सैनिक सहायता देता रहेगा. 15 अप्रैल को पाकिस्तानी दूतावास के दूसरे नंबर के अधिकारी शफाकत ककाखेल को विदेश मंत्रालय में बुलाकर सात पन्नों का एक विस्तृत ज्ञापन दिया गया.

यह ताजा ज्ञापन भारत द्वारा पाकिस्तान

कूटनीतिक शालीनता को ताक पर रखते हुए बूटा सिंह ने जिया-उल-हक के इनकार को 'झूठ का पुलिंदा' करार दे डाला

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नटवर सिंह

'दोस्ती दुतरफा होती है'

भारत के विदेश राज्यमंत्री कुंवर नटवर सिंह को अमूमन पाकिस्तान के प्रति कठोर माना जाता है. राजनयिक का पेशा छोड़ राजनीति में आए अधपके बालों वाले इस बुझारू मंत्री के मिजाज और अंदाज से भी लगता है कि वे बाज-सी पैनी निगाह रखते हैं पर ऐसी तुलना करने पर वे खफा हो उठते हैं, "बाज और फाख्ता की बात मत कीजिए. हम विदेश नीति चलाते हैं, चिड़ियाघर नहीं." हाल ही में भारत-पाकिस्तान के बीच एकाएक बढ़ गए तनाव पर नटवर सिंह से विशेष संवाददाता ***रमिंदर सिंह*** *ने बातचीत की. कुछ अंश:*

• भारत के बार-बार आरोप लगाने से कि पाकिस्तान पंजाब के आतंकवादियों की मदद कर रहा है, भारत-पाक तनाव नई बुलंदियों पर पहुंच गया है. हो क्या रहा है?

भारत-पाक रिश्तों को ऐतिहासिक संदर्भ में देखिए. सभी मानवीय भावनाएं इनसे जुड़ी हैं. इसलिए इनसे हटकर इस मुद्दे पर बहस कभी नहीं हो पाती. दो राष्ट्रों का सिद्धांत हमने कभी नहीं माना. दो राष्ट्रों के सिद्धांत को मानने का मतलब था सारे मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं. पर आज 10 करोड़ मुसलमान भारत में रहते हैं और सीमा पार भी उनके रिश्तेदार हैं. ये हालात बरकरार रहेंगे. एक देश में कुछ भी हो उसका असर दूसरे देश पर पड़ेगा ही.

• क्या सिर्फ यही वजहें हैं?

पाकिस्तान की असल दिक्कत तो उसकी पहचान को लेकर है. 41 साल पहले वहां सब मुसलमान थे. आज उनमें बलूच भी हैं, सिंधी, पठान और पंजाबी भी. उसके 33 साल तो सैनिक शासन में ही गुजरे हैं. पाकिस्तान में जब तक प्रतिनिधि सरकार नहीं बनती वह भारत के बारे में संतुलित नजरिया नहीं अपना सकता.

• यह सब आज कैसे लागू होता है?

पाकिस्तान अपने आप में ताकतवर नहीं है. इसकी आबादी भारत का आठवां हिस्सा है और क्षेत्रफल छठा हिस्सा. पर अमेरिका से मिल रही भारी सैनिक और आर्थिक सहायता की वजह से इसकी हैसियत बन गई है. पाकिस्तान तो अमेरिका की ही नुमाइंदगी करता है. अफगानिस्तान में रूस की मौजूदगी का भी उसे फायदा मिला है.

• भारत ने ये संबंध सुधारने के लिए क्या किया है?

हमने विश्वास बहाल करने के लिए मुक्त व्यापार, वीसा, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, संचार माध्यमों में विरोधी प्रचार रोकने जैसे 18 प्रस्ताव सुझाए. पर

प्रमोद पुष्करणा

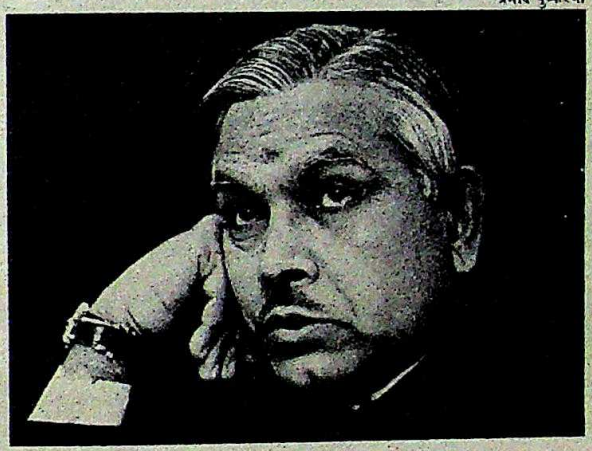

"पाकिस्तान को मिलती आ रही अमेरिकी सहायता ही इन दोनों के साथ हमारे खट्टे रिश्तों की वजह है"

पाकिस्तान ने सिर्फ मादक पदार्थ नियंत्रण में ही अपना सहयोग दिया.

• आप पाकिस्तान को मिली अमेरिकी सैनिक सहायता का जिक्र कर रहे थे.

हां, 1981 से 1987 के बीच अमेरिका ने पाकिस्तान को 7.6 अरब डॉलर की सैनिक और आर्थिक सहायता दी. इसके अलावा एफ-16 विमान और चोरी-छिपे परमाणु शस्त्रोन्मुख कार्यक्रम भी उसे मुहैया कराए गए. हाल ही में कार्लूसी ने कहा भी था कि यह सहायता जारी रहेगी. इसलिए इन दोनों देशों से हमारे खट्टे रिश्तों की यही वजह है.

• पर पिछले दो महीने में ऐसा क्या हुआ जिसकी बिना पर आप हाल के दोषारोपण को उचित ठहरा सकते हैं?

सबसे पहले तो हमें पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम की चिंता है. वह परमाणु हथियार हासिल करने के लिए पूरा जोर लगाए हुए है और लक्ष्य के काफी नजदीक पहुंच गया है. पिछले दो महीने में हमें सूचना मिली है कि वह पांच फीसदी तक यूरेनियम संवर्धन करने में लगा है.

इसके बाद है पंजाब में उसकी दखलंदाजी का मामला. हमने उसे पूरा ब्यौरा दिया है कि वह आतंकवादियों को कहां-कहां और किस तरह का प्रशिक्षण दे रहा है. फिर सियाचिन का मामला है. आखिर पाकिस्तान इस पर काबिज क्यों होना चाहता है.

और अंत में अफगानिस्तान का भी मामला है. हमारी हिस्सेदारी का स्वागत करने के बजाय वह भारत की भूमिका को ही नकारता है. वह यह तय करने वाला कौन होता है? क्या अफगानिस्तान पाकिस्तान की बपौती है?

• भारत के बयान भी काफी कड़े रहे हैं.

नहीं, हमने बहुत संयम बरता. मैं पूछता हूं 8 फरवरी के बाद पाकिस्तान की अफगान नीति क्या रही. वह कहता रहा कि वह नजीबुल्ला को मान्यता नहीं देता. अब उन्हीं के साथ उसने समझौते पर दस्तखत किए हैं. इसके अलावा दोनों के कूटनीतिक प्रतिनिधि एक-दूसरे के यहां मौजूद हैं. अजीब मजाक है?

• लड़ाई नहीं करने के संधि प्रस्ताव पर आप कुछ कहेंगे?

पंडित नेहरू ने 1949 में ऐसी संधि का प्रस्ताव रखा था. पाकिस्तान ने 1981 में इसका जवाब दिया. हमने दोस्ती और सहयोग की संधि का प्रस्ताव किया जो लड़ाई नहीं करने की संधि से कहीं आगे है. शिमला समझौता लड़ाई न करने की संधि ही है. यह आपसी रिश्तों की आधारभूमि थी. पर पाकिस्तान ने भारत की हर मुश्किल को वरदान माना. पाकिस्तान की एक सूत्री विदेश नीति है कि हर हालत में भारत का विरोध करो. जब तक पाकिस्तान अपना नजरिया नहीं बदलता और हमारी तरफ दोस्ती का हाथ आगे नहीं बढ़ाता, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी रहेगी.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

को दिया गया सबसे गंभीर आरोप पत्र था. ज्ञापन में कहा गया कि भारत के खिलाफ अलगाववादी गतिविधियों को पाकिस्तान पांच तरह से भड़का रहा है. ये हैं:

► उग्रवादी तत्वों को पनाहगाह के रूप में पाकिस्तानी इलाकों के इस्तेमाल की इजाजत देना. साथ ही उन्हें तालीम और नए कार्यकर्ता तैयार करने के लिए जगह देना,

► सिख अलगाववादियों को हथियार और गोला-बारूद उपलब्ध कराना,

► विदेश में बसे उग्रवादियों को आवाजाही की सुविधा देना,

► भारत विरोधी अलगाववादी भावनाएं भड़काने के लिए विरोधी प्रचार करना,

► और वहां जाने वाले भारतीय जत्थों (तीर्थयात्रियों) का अलगाववाद भड़काने के लिए प्रयोग करना.

नए आरोपों में सबसे गंभीर यह है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने खालिस्तान समर्थक पंथक कमेटी के दो सदस्यों—वासन सिंह और गुरबचन सिंह मनोछल को पाकिस्तान में खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के अवतार सिंह ब्रह्मा, खालिस्तान कमांडो फोर्स के गुरनाम सिंह, अखिल भारतीय सिख छात्र संघ के गुरजीत सिंह और बब्बर खालसा के वाधवा सिंह के साथ बैठक करने में सहायता की ताकि वे आतंकवादी संगठनों की साझा कमान बनाने पर बातचीत कर सकें. ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि भारतीय बैंकों से लूटी गई रकम अक्सर पाकिस्तान में पाई जाती है. मार्च 1987 में अमेरिका में एक पाकिस्तानी छात्र कशीफ महमूद को बैंक ऑफ इंडिया से लूटे गए ट्रैवलर्स चेक भुनाने की कोशिश में पकड़ा गया था. इस दस्तावेज में जगजीत सिंह चौहान समेत छह खालिस्तानी नेताओं का पाकिस्तान में स्वागत किए जाने का भी जिक्र है.

यदि सरकार के इस आक्रामक प्रचार अभियान का मकसद संसद और उसके बाहर अपने पक्ष में जनमत तैयार करना था तो एक मायने में वह कामयाब रही है. तीन वरिष्ठ पत्रकारों—प्रेम भाटिया, एस. निहाल सिंह और गिरिलाल जैन ने अपने स्तंभों और संपादकीयों में लिखा कि आतंकवादियों का पीछा ठेठ उनके पाकिस्तानी अड्डों तक किया जाना चाहिए.

पंजाब के अखबारों में खबरें छपीं कि सरकार के सख्त बयानों से सीमावर्ती गांवों में युद्ध का आतंक फैल गया है. पाकिस्तानी समाचार माध्यमों ने भी इसकी आंच महसस की और एकाएक वहां के अखबारों में सुर्खियां झलकने लगीं कि क्या युद्ध होने वाला है? वहां लड़ाई का खौफ इस कदर फैला कि जब रावलपिंडी के नजदीक ओज़री के गोलाबारूद डिपो में भयानक विस्फोट हुआ और चारों तरफ रॉकेट फटकर गिरने लगे तो वहां के लोगों ने मान लिया कि लड़ाई शुरू हो गई है.

सुरक्षा सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारियों

के.पी.एस. मेनन इस्लामाबाद में जैन नूरानी के साथ

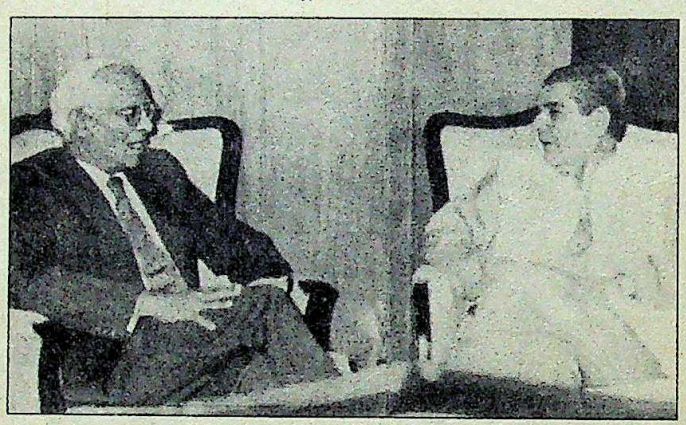

पर्यवेक्षकों के हिसाब से इस शाब्दिक गोलाबारी का कारण भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर अफगानिस्तानी और सोवियत प्रभाव है

को सियाचिन में ज्यादा परेशानी का अंदेशा है. सियाचिन में मुंहकी खाने से जिया के सैनिक और प्रशासनिक रिकार्ड पर धब्बा लग गया है. और इस महत्वपूर्ण ग्लेशियर को वापस पाने के लिए पाकिस्तान जो कुछ कर सकता है, जरूर करेगा. सियाचिन का मौसम अप्रैल में साफ होता है और आम तौर पर सितंबर तक साफ रहता है. इसलिए पाकिस्तानी सेना का कोई भी हमला इन्हीं बीच के महीनों में हो सकता है. इसी वजह से मेनन मानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में सियाचिन तनाव का कारण बना रहेगा.

भारतीय सुरक्षा के रणनीतिज्ञ सऊदी अरब से पाकिस्तानी थलसेना की एक डिवीजन की वापसी को लेकर भी चिंतित हैं. अब पाकिस्तान इस डिवीजन को भारतीय सीमा पर तैनात कर सकता है. इसके साथ मुजाहिदीनों के लिए आए हथियारों को भारत की ओर मोड़ा जा रहा है. इससे नई अनिश्चितताएं पैदा होंगी. एक पाकिस्तानी कूटनयिक का कहना था, "भारत ने पाकिस्तान की ओर हमेशा अपनी सुरक्षा के नजरिये से ही देखा है, कभी राजनैतिक संदर्भों में नहीं देखा. इससे पता चलता है कि भारत किस हद तक सैनिक विकल्प को अहमियत देता है हालांकि सामरिक पलड़ा तो उसी की तरफ झुका हुआ है."

दिल्ली में ज्यादातर कूटनीतिक पर्यवेक्षकों को लगता है कि अफगानिस्तान के बदलते हालात का असर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर पड़ रहा है और उसी वजह से पाकिस्तान के खिलाफ आरोपों की बौछार भी तेज हुई है. पाकिस्तान पर भारत के आरोप जेनेवा समझौते पर दस्तखत होने के आसपास ही उग्र से उग्र होते गए.

लेकिन हो सकता है देश में पड़ रहे दबावों ने भी राजीव गांधी को पंजाब के मसले पर पाकिस्तान की ओर टेढ़ी नजर करने पर विवश किया हो. उन्हें एक बलि के बकरे की जरूरत थी जिस पर वे पंजाब समस्या का दोष मढ़ सकें. यदि चुनाव के आसार दिखे (अच्छी बारिश होने पर जिसकी पूरी संभावना है) तो वे पंजाब को अव्यवस्था की स्थिति में बने रहने देने की जिम्मेवारी अपने सिर लेने का खतरा नहीं उठा सकते. इसलिए बलि के बकरे की तलाश होगी.

यहां यह नहीं सुझाया जा रहा है कि पाकिस्तान पर कोई इल्जाम नहीं लगाया जा सकता या वह आतंकवादियों को सहायता और छुपने की जगह नहीं दे रहा है. सचाई शायद भारत के आरोपों और पाकिस्तान के खंडनों के बीच कहीं है. पंजाब में आतंकवादियों और उग्रवादियों से जिस किसी ने भी बातचीत की है वह अच्छी तरह जानता है कि उन्हें पाकिस्तान में पनाह और वहां से वित्तीय सहायता तथा हथियार आसानी से मिल रहे हैं. त्रासदी तो यह है कि भारत सरकार जब अपने ज्ञापन में यही आरोप लगाती है तो उसके साथ ऐसे सबूत नहीं पेश करती जिनसे 'अकाट्य' होने के विशेषण को जायज ठहराया जा सके.

—रामेश्वर सिंह

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

परमाणु प्रक्रिया से परहेज

कंपनियां अपने खाद्य उत्पादनों के 'परमाणु किरणन' के लिए बेताब हैं और सरकार ऐसा होने नहीं दे रही है. रैलीज इंडिया महाराष्ट्र और केरल में ऐसे दो प्लांट लगाना चाहती थी जिन पर 9.29 करोड़ रु. खर्च होते और उनमें 2.6 लाख टन फल-सब्जियों और दस लाख घन फीट मसालों को परमाणु किरणन से गुजारने की व्यवस्था होती. किरणन प्रक्रिया से फल-सब्जियों में मौजूद सूक्ष्म कीड़े मर जाते हैं. कई वैज्ञानिकों द्वारा इस प्रक्रिया को एकदम सुरक्षित बताने के बावजूद स्वास्थ्य मंत्रालय की नेशनल मोनिटरिंग एजेंसी ने किसी भी योजना को मंजूरी नहीं दी. सरकार ने दोनों प्रस्तावों को खारिज कर दिया.

बंगलूर पर धावा

बंगलूर में मुख्यालय बनाने या अपना दफ्तर खोलने के लिए कंपनियों की दौड़ जारी है. माल्या समूह की कंपनियों के यहां पहुंचने के बाद लिप्टन और ब्रुक बांड यहां आए. अब ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज आ रही है. 192 करोड़ रु. कारोबार वाली इस कंपनी ने अपने दफ्तर और कुछ लोगों के आवास के लिए 2.2 एकड़ जमीन खरीद ली है. बंबई से दफ्तर हटाने का कारण पश्चिमी इलाके के महानगरों में जायदाद की कीमत बहुत ऊंची होना है. वहां दफ्तर रखने से पैसा बहुत खर्च होता और निवेश की दूसरी योजनाएं मुश्किल में पड़तीं. अब यह गिनती की जाने लगी है कि और कौन सी कंपनियां बंगलूर जाएंगी. इनमें एचएमएम, डॉडसाल, फेनर और जॉनसन ऐंड जॉनसन का नाम लिया जा रहा है.

बिड़ला को इनकार

लगता है कि बिड़ला परिवार पेट्रोकेमिकल परियोजनाओं को बड़े पैमाने पर लेने का फैसला कर चुका है. आदित्य बिड़ला समूह द्वारा एक बड़े तेलशोधक संयंत्र का काम हाथ में लेने के बाद जी.पी. बिड़ला समूह ने विशाखापत्तनम में 125 करोड़ रु. की लागत से उच्च घनत्व वाले पोलिथिलीन की परियोजना लेने की कोशिश की थी. एम.पी. बिड़ला समूह की यूनिवर्सल केबल्स कंपनी ने भी 65 करोड़ रु. की लागत से पोलिथिलीन परियोजना की अनुमति मांगी थी. लेकिन सरकार ने दोनों ही आवेदनों को इस आधार पर मंजूर नहीं किया कि अभी इतनी पोलिथिलीन के लिए कच्चा माल देने वाली इकाइयों को लाइसेंस नहीं दिया गया. वैसे ऐसा होते ही ये कंपनियां फिर से अर्जी दे सकती हैं.

विदेशी आकर्षण

ब्रिटेन की कंपनी 'आईसीआई' इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड में लगे अपने सारे शेयर नहीं बेचेगी, यह आशंका निर्मूल नहीं हो सकती. विस्फोटक, रासायनिक खाद, पेंट और दूसरे धंधों में लगी इस कंपनी को आंशिक (या पूरी) खरीदने के लिए जब विदेशी कंपनियों पर नजर गड़ाए पैसे वाले भारतीयों ने इस ब्रिटिश कंपनी से संपर्क किया तो उसने एक बार में किसी को 'ना' नहीं किया. एक समस्या तो यह है कि आईईएल के कुछ शेयर सरकार के पास भी हैं और इस कारण उसका सौदा दूसरी विदेशी कंपनियों के हुए सौदों जैसा नहीं हो सकता. और फिर आईसीआई जब अपने 50 फीसदी से अधिक शेयरों को बेचना चाहेगी तो उसे कदम-कदम पर सरकारी अनुमति लेनी होगी. मामला चाहे जो हो लेकिन जो व्यापारी कंपनियों की खरीद से ही विकास करने की नीति पर चलते हैं, उनके लिए यह अब आकर्षण का केंद्र रहेगी.

व्यावसायिक दिग्गज

सार्वजनिक क्षेत्र और उसकी कुशलता को लेकर कभी-कभार बहस छिड़ती रहती है लेकिन यह ठोस तथ्य है कि औद्योगिक मामलों में सार्वजनिक क्षेत्र इतनी बड़ी हस्ती बन चुका है कि न तो उसे चुनौती दी जा सकती है, न उसकी स्थिति में बदलाव लाया जा सकता है. हाल में सरकार द्वारा जारी आंकड़े बताते हैं कि मार्च 1987 के अंत तक सभी कंपनियों में लगी पूंजी

चार्ट: बी.के. शर्मा

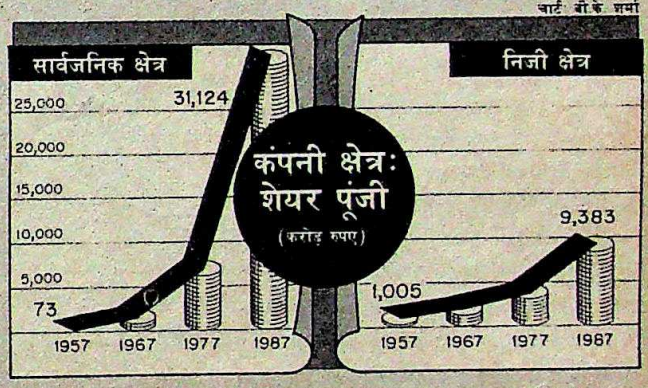

का 76.83 फीसदी हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में लगा था. 30 साल पहले यह मात्रा सिर्फ 6.74 फीसदी थी. सरकारी कंपनियां पूंजी के मामले में 1960 के दशक के आखिर में निजी कंपनियों से आगे निकली हैं और इनकी पूंजी में सबसे तेज वृद्धि पिछले पखवाड़े में हुई. इसी का नतीजा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की कुल शेयर पूंजी पिछले साल 31,124 करोड़ रु. हो गई, जबकि निजी क्षेत्र की शेयर पूंजी 9,383 करोड़ रु. ही रही.

तकरार और तरक्की

मोदी परिवार की आपसी तकरार से उनकी नई योजनाओं में पूंजी निवेश और नया काम शुरू करने में कोई बाधा आती नहीं दिखती. स्पार्क प्लग बाजार (जिस पर पहले मोटर इंडस्ट्रीज का प्रभुत्व था) में अपनी कंपनी मोदी चैंपियन शुरू करने के बाद केदारनाथ मोदी परिवार (जिसके पास अपने नियंत्रण वाली कुछ ही कंपनियां थीं) अब दूसरे पुर्जों फिल्टर, तार, केबल्स और रसायन बनाने की योजना बना रहा है. इसके लिए उसने अमेरिका की चैंपियन स्पार्क प्लग कंपनी से गठबंधन किया है. इसके साथ ही ओडीसा सरकार के सहयोग से उसी राज्य में 350 करोड़ रु. की कैप्रोलैक्टम योजना शुरू करने की तैयारी चल रही है. इसके लिए तकनीकी सहयोगी ढूंढने के लिए विदेशों में बात हो रही है. कैप्रोलैक्टम बनाने वाली दुनिया में तीन ही बड़ी कंपनियां हैं और संभावना है कि जापानी कंपनी से गठबंधन हो जाए.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मजदूर संघ

मालिकों की टेढ़ी नजर

प्रबंधक छंटाई, वेतन वृद्धि रोकने, सुविधाएं घटाने के मूड में

कलकत्ता में ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया ने अपने मजदूर संघों से प्रति मजदूर अधिक उत्पादकता देने, तीन साल तक वेतन में किसी तरह की वृद्धि रोकने और पांच मिनट देर से आने वाले कर्मचारियों को काम पर न आने देने जैसी शर्तों पर अपनी रजामंदी देने को कहा है.

फरीदाबाद की आइशर ट्रैक्टर्स ने ओवर-टाइम बंद कर दिया है और पिछले साल अपने मजदूर संघों से उत्पादकता के अनुसार वेतन घटाने-बढ़ाने और भत्तों में कटौती का एक समझौता कर लिया.

बंबई में ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने पिछले अप्रैल में अपने मजदूर संघों के साथ एक समझौता किया जिसके मुताबिक कामगार उत्पादन में 10 फीसदी बढ़ोतरी करेंगे.

और ये उदाहरण अपवाद भर नहीं हैं बल्कि देश भर की कई कंपनियां मजदूरों से सख्ती बरतने, उनसे ज्यादा उत्पादन की मांग और महंगाई भत्ते पर हदबंदी लगाने या मजदूरों की छंटनी करने में जुटी हैं. पिछली जुलाई में डनलप इंडिया ने मजदूर संघ के साथ बोनस को उत्पादकता से जोड़ने और वैधानिक रूप से तय बोनस को बदलने का समझौता किया. मद्रास में वेलकम ग्रुप के चोल-शेरटॉन होटल ने भी यही किया. पिछले साल एन्फील्ड इंडिया ने अपने मोटर साइकिल कारखाने में 170 मजदूरों से छुट्टी पा ली. इनमें से अधिकांश प्रशिक्षु कर्मचारी थे.

करीब 18 महीने पहले बंबई की विमको कंपनी ने काम की मात्रा के अनुसार वेतन लेने वाले मजदूरों से साफ-साफ कह दिया कि कंपनी की माचिसों का आकार बदलने पर उनकी मजदूरी की दर संशोधित नहीं की जाएगी. और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) ने अपने कर्मचारियों को अवकाश लेने के लिए प्रोत्साहित करके पिछले दो वर्षों में कंपनी में पदों की संख्या कम कर ली है.

हालांकि अभी भी सभी कंपनियां सख्त रवैया नहीं अपना रही हैं. मसलन बंबई की प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स अपने कर्मचारियों को हर महीने 2,000 रु. महंगाई भत्ता देती है. वेतन के मामलों पर ताजा बातचीत से इसमें और बढ़ोतरी की उम्मीद है. पर प्रीमियर के अध्यक्ष विनोद दोषी और मल्कानी मानते हैं कि ज्यादा वेतन अब ज्यादा उत्पादकता से जोड़ दिया गया है.

कंपनियों के प्रबंधक वाकई अब ज्यादा आक्रामक ढंग से अपनी मांगें रख रहे हैं. इंटक के पश्चिम बंगाल के नेता सुब्रत मुकर्जी इस प्रवृत्ति के बारे में खेद के साथ कहते हैं, "उद्योग अब अपनी मांग पेश कर रहे हैं, मजदूर संघों के जुझारू होने के बदले प्रबंधक ही अधिक जुझारू होते जा रहे हैं."

यह परिवर्तन ज्यादातर भारी घाटे वाली कंपनियों और पश्चिम बंगाल में दिखता है जहां मुश्किलों में पड़े उद्योगों (जूट, इंजीनियरिंग) की संख्या कहीं अधिक ही है. मरणासन्न मेटल बॉक्स कंपनी में प्रबंधकों ने वेतन वृद्धि में कटौती और वृद्धि रोके रहने की मांग रखी है.

लेकिन एक दशक पहले तक ऐसा रवैया अपनाना संभव नहीं था. अब मजदूरों को डराया-धमकाया भले ही नहीं जा रहा हो पर उनकी गरदन पकड़ने की कोशिश तो चल ही रही है. कलकत्ता में ग्रामोफोन कंपनी के अध्यक्ष प्रदीप चड्ढा कहते हैं, "ज्यादातर मजदूर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

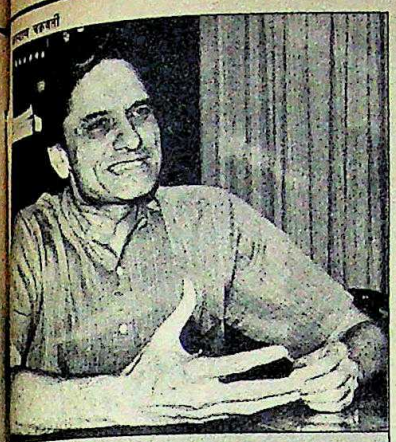

"प्रबंधकों पर दबाव पड़ रहा है इसीलिए वे सख्त रवैया अपनाते जा रहे हैं"

रमेश माहेश्वरी
अध्यक्ष, टेक्समेको

"मजदूर संघों के जुझारू होने के बदले प्रबंधक ही उनसे अधिक जुझारू होते जा रहे हैं"

सुब्रत मुकर्जी
इंटक नेता

"प्रबंधक मजदूरों के प्रति सख्ती नहीं बरत रहे हैं. उनका रुख जरा सुदृढ़ भर हुआ है"

विनोद दोषी
अध्यक्ष, प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स

...ता अब नौकरियां बचाने पर जोर देते हैं."

औद्योगिक वातावरण भी बदल गया है और प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है. प्रतिस्पर्धा से ...मना होने के साथ ही कंपनियां उत्पादन ...र्च, सूद की दरों और अपनी दूसरी गति-...धियों में कड़ाई बरतने लगी हैं और हाथ ...भालकर खर्च करने लगी हैं. आडवाणी-...लिकॉन के मल्कानी कहते हैं, "लागत कम ...रने की फेहरिस्त में अब मजदूरी भी जुड़ ...ई है. बाजार की हालत का हमारे कामकाज ...र असर तो पड़ेगा ही."

लागत बढ़ाने में महंगाई भत्ते की बड़ी भूमिका है. नियोजकों के अखिल भारतीय संघ ने बंबई के मूल्य सूचकांक और मुद्रास्फीति की 10 फीसदी दर के आधार पर एक सर्वेक्षण करवाया है जो अभी छपना है. इसके अनुसार 1991 तक कंपनियों को 100 रु. मूल वेतन वाले कर्मचारी को 2,705 रु. महंगाई भत्ता देना पड़ेगा जबकि 1984 में इसकी अधिकतम रकम 1,555 रु. थी. 550 रु. मूल वेतन पर महंगाई भत्ता 5,000 रु. की सीमा पार कर जाएगा.

लेकिन यह भी सही है कि ऐसे हालात बनने की जिम्मेवारी से प्रबंधक भी नहीं बच सकते. टेक्समेको के अध्यक्ष रमेश माहेश्वरी कहते हैं, "प्रबंधकों पर दबाव पड़ रहा है इसलिए वे सख्त रवैया अपना रहे हैं." पर उनका मानना है कि प्रबंधक माकूल माहौल बनाने में नाकामी का दोष मजदूरों पर मढ़कर बचना चाहते हैं.

पर ज्यादातर प्रबंधक सख्ती बरतने के हिमायती नहीं हैं. उनके मतानुसार यह महज सुदृढ़ रवैया है. प्रीमियर के दोषी कहते हैं, "प्रबंधन मजदूरों के प्रति सख्ती नहीं बरत रहा. उसका रुख सुदृढ़ भर हुआ है." प्रबंधक सख्त हो रहे हों या रवैया सुदृढ़ कर रहे हों उनका नजला मजदूरों पर ही गिर रहा है. विरोधियों का मानना है कि प्रबंधकों को वर्षों बाद लगा कि वे मजदूरों के हाथों अपने विशेषाधिकार खो बैठे हैं.

ऐसा आत्म-विश्लेषण बहुत व्यापक नहीं है. यदि इसने गति पकड़ी तो प्रबंधन सचमुच सख्त रवैया अपनाने लग सकता है वह भी उच्च स्तर पर, जहां इसकी अहमियत ज्यादा है.

—पलकुन्नथु जी. मथाई और एस.एच. वेंकटरमनी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शेयर बाजार

तेजी का दौर

हर लक्षण उम्मीद भरा

पिछले पखवाड़े शेयर बाजार में जो आत्मविश्वास दिखा उसकी कोई सीमा नहीं थी. दो हफ्ते से कम समय में शेयर मूल्यों में करीब 10 फीसदी वृद्धि हुई और इसके बाद थोड़ी कमी. लेकिन इस कमी के बाद बाजार फिर चढ़ने को तैयार लगा. लगता था जैसे वित्त वर्ष की समाप्ति पर संपत्ति कर के झमेले से पैदा हुई मंदी कृत्रिम थी और बाजार अब सामान्य कीमतों के स्तर पर लौट रहा है.

सरकार ने भी इस प्रक्रिया में मदद की है. वित्तमंत्री नारायणदत्त तिवारी ने निवेशकों और दलालों की उम्मीद के अनुसार रियायतों की घोषणा की: निवेश भत्ता फिर से वापस आया और निर्यात के मुनाफे पर न्यूनतम कर खत्म कर दिया गया. होटल उद्योग को भी उसकी मुंहमांगी रियायतें मिलीं.

चार्ट बी.के. शर्मा

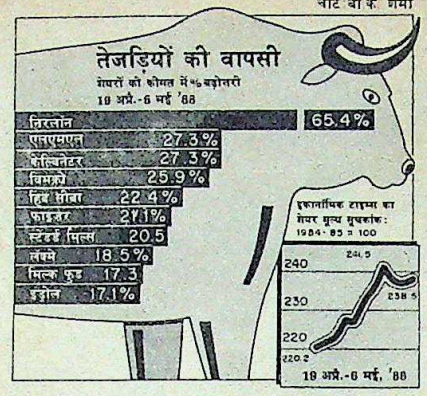

शेयर बाजार के अधिकारियों द्वारा दवे कमेटी की और सिफारिशें लागू करने से कामकाज सुधरा और उत्साह बढ़ा. अनेक कंपनियों ने बेहतर वार्षिक कारोबार की घोषणा की. इनमें रिलायंस भी शामिल थी.

रिलायंस के शेयर इसी साल के अपने न्यूनतम स्तर से करीब दुगनी कीमत पर (69 रु. की जगह 127.50 रु.) बिके. इससे कंपनी के मुनाफे की स्थिति में हुए बदलाव के बारे में बाजार की राय पता चलती है. दिक्कतें झेल रही कंपनी निरलॉन के शेयर भी पिछले पखवाड़े अद्भुत गति से ऊपर चढ़े और फिर एक बार मूल कीमत से भी ऊपर बिकने लगे. उत्साह के इस माहौल में अपने मुनाफे के सबसे अच्छे स्तर तक भी नहीं पहुंची कंपनियों के शेयर भी काफी चढ़े. विमको, फाइज़र के भी.

नतीजतन इकानॉमिक टाइम्स शेयर मूल्य सूचकांक पूरे पखवाड़े धीरे-धीरे चढ़ता रहा. यह 19 अप्रैल के 220.2 से बढ़कर दो मई को 241.5 पर आया. फिर पखवाड़े के अंत में गिरकर 238.5 पर आ गया. अच्छी कीमत मिलने पर कई निवेशकों ने खुशी-खुशी अपने शेयर निकाल दिए. लेकिन बाजार के नए मूड पर ऐसे शेयरों के निकलने से फर्क नहीं पड़ा और इस कारण कोई गिरावट नहीं आई.

भविष्य अब मानसून के सही समय पर और सही मात्रा में आने पर निर्भर करता है. शुरुआती सारे लक्षण उम्मीद जगाते हैं और मौसम विभाग की भविष्यवाणी भी आशाजनक है. और अगर यह ठीकठाक हुआ तो दो साल की मंदी के बाद बाजार फिर उफान की स्थिति में पहुंच सकता है. 1985 के बाद से निवेशकों के लिए कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं लग रही थी. कुछ महीने की सुस्ती के बाद तेजड़ियों का बाजार फिर तेज होगा वरना अभी तक तो बेचारे मंदड़ियों के हाथ पिट ही रहे थे.

जमा स्टॉक

	1988 ऊंचा	1988 नीचा	1988 बंद 6.5.88	पखवाड़े में स्टॉक की स्थिति
अशोक लेलैंड	36.50	30.25	33.25	0.25 −
एसोसिएटेड सीमेंट	180.00	128.50	167.00	8.50 +
एटलस कोप्को	63.50	33.50	44.00	4.00 +
एशियन पेंट्स	169.00	128.75	147.50	10.00 +
बजाज ऑटो	520.00	187.50	198.75	1.25 +
बड़ौदा रेयॅन	237.50	140.00	235.00	20.00 +
बाटा इंडिया	71.50	50.50	61.50	0.75 +
बेयर	335.00	280.00	320.00	15.00 −
भारत फोर्ज	126.50	101.00	120.00	6.00 +
बिरला जूट	44.00	32.25	36.00	1.70 −
ब्लो प्लास्ट	125.00	28.00	37.00	1.00 +
बॉम्बे डाइंग	138.00	94.00	128.50	10.50 +
ब्रिटानिया इंडिया	109.00	75.00	85.00	7.00 +
ब्रुक ब्रांड	98.00	75.00	94.00	6.00 +
सीएट टायर्स	88.00	55.00	60.00	5.00 −
सेंचुरी स्पिनिंग	842.50	617.50	832.50	75.00 +
क्लोराइड इंडिया	80.50	59.00	65.00	3.00 +
कोलगेट	220.00	160.00	179.00	14.00 +
सायनामिड	49.00	33.00	41.50	2.00 +
डीसीएम	42.00	28.00	33.00	1.00 +
डनलप	83.00	71.00	74.00	0.50 −
ईआई होटल्स	54.00	38.00	52.00	5.00 +
एस्कार्ट्स	45.00	37.00	43.50	4.00 +
फिनोलेक्स केबिल्स	380.00	272.50	317.50	35.00 +
फूड स्पेशिलिटीज	142.00	93.50	112.50	11.00 +
गरवारे नाइलोन	38.00	20.00	35.50	1.00 −
जी.ई. शिपिंग	28.87	20.50	26.36	1.40 −
गुजरात स्टेट फर्टि.	118.00	75.00	104.00	11.50 +
ग्रासिम इंडिया	104.75	81.50	95.00	6.50 +
हिंदु. एल्यूमिनियम	139.00	73.00	78.00	5.00 +
हिंदुस्तान सिबा	480.00	332.50	465.00	75.00 +
हिंदुस्तान कोकोआ	215.00	67.50	77.50	6.50 +
हिंदुस्तान लीवर	81.00	59.50	73.00	8.00 +
हिंदुस्तान मोटर्स	25.00	15.80	17.80	1.00 +
आई.ई.एल.	43.75	31.00	35.00	2.00 +
इंडियन आर्गेनिक	25.00	15.00	19.50	—
इंडियन रेयॅन	64.00	46.00	63.50	6.00 +
इंड्राल	223.75	133.75	162.50	22.50 +
इंगरसॉल-रैंड	335.00	205.00	245.00	32.50 +
आई.टी.सी.	39.75	30.00	36.50	3.50 +
जे.के. सिंथेटिक्स	69.00	45.50	56.00	6.50 +
काइनेटिक इंजी.	205.00	161.25	191.25	16.25 +
किर्लोस्कर क्युमिस	58.00	48.00	56.00	1.00 +
केएसबी पम्प्स	425.00	215.00	262.50	25.00 +
लारसन-टुब्रो	95.50	75.50	86.00	4.00 +
लिप्टन	67.00	52.00	63.00	3.00 +
लोहिया-मशीन्स	15.00	9.00	14.00	3.00 +
मदुरै कोट्स	77.00	59.00	72.00	1.00 +
महिंद्रा-महिंद्रा	63.00	48.50	58.50	6.50 +
मोटर इंडस्ट्रीज	587.50	447.50	515.00	40.00 +
मुकुंद आयरन	95.00	72.50	91.50	4.50 +
नेशनल आर्गेनिक	525.00	390.00	465.00	15.00 +
निरलॉन	12.50	5.00	10.75	3.50 +
ओरके सिल्क मिल्स	30.00	17.00	23.00	1.00 −
ओटिस एलिवेटर	215.00	161.25	180.00	13.75 +
पेइको इलेक्ट्रॉनिक्स	34.00	24.50	31.50	3.75 +
फाईजर	79.50	50.00	66.00	11.00 +
प्रीमियर ऑटो	31.00	23.00	28.50	2.25 +
रैनबेक्सी	102.50	76.00	95.00	11.00 +
रेमंड	96.00	41.50	45.00	1.75 +
रॉकिट ऐंड कोलमैन	214.00	175.00	190.00	6.00 +
रिलायंस इंडस्ट्रीज	128.00	69.00	127.50	19.00 +
शॉ वैलेस	132.00	50.50	54.50	1.00 +
सीमेन्स इंडिया	80.00	56.00	66.00	7.00 +
श्रीराम फाइबर्स	47.00	32.50	44.75	6.25 +
एसकेएफ बैयरिंग्स	1365.00	1058.00	1310.00	95.00 +
स्पिक	37.00	23.50	34.00	4.40 +
टाटा स्टील	720.00	568.75	707.50	12.50 +
टेल्को	515.00	340.00	510.00	50.00 +
विम्को	24.00	11.00	17.00	5.00 +

भारतीय रुपए का मूल्य

देश	मुद्रा	इकाई	क्रय मूल्य (रुपए में)	बिक्री मूल्य (रुपए में)
आस्ट्रेलिया	डालर	1	10.2488	10.1396
आस्ट्रिया	शिलिंग	1	1.1314	1.1192
बहरीन	दीनार	1	34.9893	34.9160
बांग्लादेश	टका	100	41.7930	41.7086
कनाडा	डालर	1	10.8468	10.7351
डेनमार्क	क्रोना	1	2.0624	2.0410
मिस्र	पौंड	1	9.3430	9.3020
फ्रांस	फ्रैंक	1	2.3781	2.3121
हांगकांग	डालर	1	1.7144	1.6970
इंडोनेशिया	रुपिया	100	0.0078	0.0073
ईरान	रियाल	100	19.6122	19.5832
इटली	लीरा	100	1.0786	1.0637
जापान	येन	100	10.8500	10.5500
केन्या	शिलिंग	1	0.7436	0.7081
कुवैत	दीनार	1	48.4232	48.4831
मलेशिया	डालर	1	5.1819	5.1266
मारीशस	रुपया	1	1.0581	1.0090
नेपाल	रुपया	1	0.6200	0.6000
हालैंड	गिल्डर	1	7.0838	7.0100
पाकिस्तान	रुपया	1	0.7380	0.7000
सिंगापुर	डालर	1	6.6824	6.6097
स्पेन	पेसो	1	0.1200	0.1100
श्रीलंका	रुपया	1	0.4290	0.4083
स्वीडन	क्रोना	1	2.2723	2.2488
स्विट्जरलैंड	स्विस फ्रैंक	1	9.5300	9.4290
तंजानिया	शिलिंग	1	0.1499	0.1301
थाईलैंड	बहत्त	100	52.9280	52.8032
ब्रिटेन	पौंड	1	24.8275	24.6900
सं. राज्य अमेरिका	डालर	1	13.3850	13.2525
सं. अरब अमीरात	दिरहाम	1	3.6032	3.5218
सोवियत संघ	रूबल	1	22.2332	22.1688
पश्चिम जर्मनी	जर्मन मार्क	1	8.0775	7.8740

स्रोत—बैंक ऑफ टोक्यो, नई दिल्ली, 6.5.88

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

RW

RAYMOND WEIL
COLLECTION

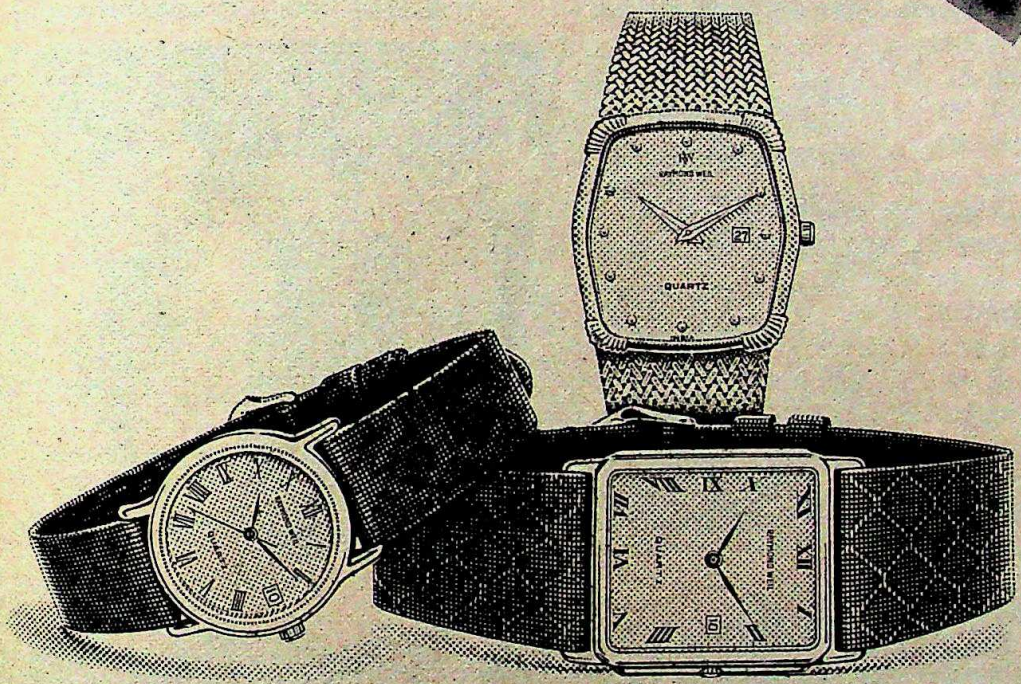

THE FASCINATION NEVER ENDS

Raymond Weil
Jewellery Watches. Ultra-thin.
Quartz. 18-carat goldplated.
A new dimension in elegant,
exclusive wristwear.

Dattaram-RW 3A/87

An RW Product. Made in India with technical assistance from Raymond Weil, Geneve ☐ Goel Private Limited, 95-C Mittal Tower, Nariman Point, Bombay-400 021.

Selected Watch & Jewellery Stores (Telephone Nos.): BOMBAY: Tribhovandas Bhimji Zaveri: 341010 ● Apsara Pen Mart: 271101 ● Cliftons: 264288 ● J.K. Time: 6490011 ● Lawrence Watch Co: 2048416, 2040130 ● Marcks & Co: 270999 ● Akbarallys: 6490612 ● Eastern Watch: 264711 ● Anja San: 6420801 ● PUNE: Pundole Enterprises: 446275, 63685 ● DELHI: Johnson Watch Co: 3322002 ● Fine Watch Co: 264636 ● Aar-tee Watch Emporium: 2527044 ● Big Ben: 3320216 ● LUCKNOW: Rupani Bros: 43619 ● KANPUR: Thakurdas Jewellers: 61146. ● CALCUTTA: Rams: 431590 ● MADRAS: Doshi & Doshi: 565118, 560963 ● Chhotabhai & Co: 32024 ● SECUNDERABAD: Ramesh Watch Co: 72649 ● AHMEDABAD: Vajubhai Jewellers: 401901 ● Kenya Watch Co: 448035 ● Favourite Watch Co: 78395.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विशिष्ट खेल कार्यक्रम

बूंद से मोती बनाने का अभियान

देश के विभिन्न इलाकों की प्रतिभाएं खेल क्षितिज पर चमकेंगी

लद्दाख के बर्फीले रेगिस्तान से लेकर धुर पूर्व में मिजोरम और मणिपुर के जंगलों तक और छोटानागपुर पठार के वनवासी इलाकों से लेकर केरल में धान के भंडार कुट्टनाड तक इन दिनों एक अनूठा खोज अभियान जोरों से चल रहा है. विभिन्न खेलों के पारखी देश भर के ऐसे इलाकों में होनहार खिलाड़ियों को ढूंढ़ निकालने में लगे हुए हैं जिधर कभी खेल विशेषज्ञों ने निगाह भी नहीं डाली थी. अब तक के इस सबसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का उद्देश्य भविष्य के लिए एक नई और भरोसेमंद भारतीय पौध तैयार करना है.

यह अभियान भारतीय खेल प्राधिकरण के विशिष्ट खेल कार्यक्रम के अंतर्गत चलाया जा रहा है. इसमें क्षेत्र विशेष के लोगों की आनुवंशिक और स्थानीय विशिष्टताओं को ध्यान में रख विशिष्ट खेलों के लिए खिलाड़ियों के चयन की नीति अपनाई गई है.

इस चयन प्रक्रिया में ऐसी मान्यताएं ध्यान में रखी गई हैं जो वैज्ञानिक कसौटी पर तो खरी उतरती हैं पर अभी तक उनका इस्तेमाल नहीं किया गया. उदाहरण के लिए गुजरात के गीर जंगलों, कर्नाटक के उत्तरी कनारा जिले और हैदराबाद में रहने वाली सिद्दी जाति भारत की इकलौती अफ्रीकी जाति है. आनुवंशिक तौर पर शानदार धावकों की जाति मानी जाने वाली सिद्दी जाति केन्या की कालेनजिन और कीसी कबीलों से मिलती-जुलती है. इसके धावकों ने 1963 से अब तक अंतरराष्ट्रीय दौड़ प्रतियोगिताओं में पदकों के

भारतीय खेलों की महत्वाकांक्षी योजना का मकसद है नई भरोसेमंद पौध तैयार करना. इसके तहत क्षेत्र विशेष के लोगों की आनुवांशिक और स्थानीय विशेषताओं के मद्देनजर खिलाड़ी तैयार किए जाएंगे

सिद्दी धावक (नीचे), और अलेप्पी में नौकायन

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Haridwar.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बार जुटाए हैं. इस कार्यक्रम के तहत जिन मान्यताओं की परीक्षा की जा रही है उनमें से एक यह है कि ऊंचे क्षेत्रों में रहने वाले एथलीटों की सहनशक्ति समुद्र तल के स्तर पर रहने वाले लोगों के मुकाबले बेहतर होती है. दूसरी मान्यता के अनुसार मंगोलियाई नस्ल के लोग कुश्ती और कुश्ती जैसे खेलों में बेहतर होते हैं. इसी तरह यह प्रयोग भी किया जा रहा है कि क्या केरल के ओणम त्यौहार में नौका प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली टीमों को अंतरराष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिताओं में उतारकर पदक जीते जा सकते हैं.

पहला अभियान 1986 नवंबर में तीरंदाजी में शुरू किया गया. परिणाम तेरह महीने में ही सामने आ गया. उदयपुर में 8 रु. दिहाड़ी पर खेतों में मजदूरी करने वाले 18 वर्षीय लिंबा राम और बांसवाड़ा के 20 वर्षीय श्यामलाल ने बांस की परंपरागत कमान छोड़कर अंतरराष्ट्रीय किस्म की कमान पर ऐसा कमाल दिखाया कि 1984 से 1987 तक राष्ट्रीय चैंपियनशिप पर कब्जा जमाए बैठे संजीव सिंह को पीछे छोड़ दिया. आज देश के चोटी के 10 तीरंदाजों में संजीव सिंह को छोड़ शेष इसी कार्यक्रम के दौरान चुने गए हैं.

संजीव कहते हैं, "वे अचानक इस मैदान में आए और छा गए." साल में पहली बार श्यामलाल ने ही एशियाई चैंपियनशिप में भारत को तीरंदाजी में पहला कांस्य पदक दिलाया. नए कार्यक्रम पर नजर रखने वाली विशेष खेल प्राधिकरण समिति की अध्यक्ष और केंद्रीय खेल और युवा कल्याण राज्यमंत्री मार्गरेट अल्वा कहती हैं, "तीरंदाजी के गांवों में लोग आज भी एक लंबी कमान और जंगल में घूमते रॉबिनहुड जैसी कल्पनाएं करते हैं. हमारे प्रशिक्षण के आधार पर युवा खिलाड़ियों ने दिखा दिया है कि तीरंदाजी तकनीकी मामला है और मांसपेशियों के संचालन और मानसिक स्थिति पर निर्भर है."

प्रतिभा खोज की दिशा में पहला कदम किसी खेल विशेष में रुचि और रुझान का सर्वेक्षण करना होता है. उसके बाद कार्यक्रम से जुड़े अधिकारियों का एक दल उस इलाके में जाता है और परीक्षणों तथा प्रतियोगिताओं के बाद होनहार खिलाड़ियों का चयन करता है. इसके बाद दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इन खिलाड़ियों की शारीरिक क्षमताओं की कड़ी जांच होती है. इनमें से केवल अच्छे दर्जे के खिलाड़ियों को ही साल भर के निरंतर प्रशिक्षण के लिए चुना जाता है. जहां उनकी योग्यताओं को जमकर निखारा जाता है.

कार्यक्रम के प्रधान 33 वर्षीय आईएएस अधिकारी बी.वी.पी. राव इन दिनों खेल चिकित्साशास्त्रियों, समाज वैज्ञानिकों और पुराने अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों तथा खेल आयोजकों का एक दल तैयार करने में लगे हैं. यह दल 9 से 22 वर्ष की आयु वाले 400 लड़के-लड़कियों को 10 खेलों में प्रशिक्षण देगा. इस कार्यक्रम के तहत नेहरू स्टेडियम के अलावा देश के दूसरे स्थानों पर भी प्रशिक्षण केंद्रों का चुनाव किया गया है, जहां किसी विशेष खेल की सुविधाओं और प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है.

पानी वाले खेलों के लिए केरल के अलेप्पी जिले के अखबारों में विज्ञापन दिए गए और 800 आवेदकों में से 180 को 1987 की ओणम नौका प्रतियोगिता के बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया गया. इनमें से केवल 17 को ही प्रशिक्षण के लिए चुना गया. इनमें से 4 को डोंगी चालन, 7 को नौकायन और 6 को चप्पू नौकायन में प्रशिक्षित किया जा रहा है. केंद्र के प्रशासक सी.कृष्णकुमार (34) बताते हैं, "प्रशिक्षण में इन लड़कों की वैसी ही रुचि है जैसी मछली की पानी में होती है. केवल 17 का चुनाव इसलिए किया क्योंकि केवल उन्हीं में अकेले या जोड़ी में नौका दौड़ में हिस्सा लेने की शारीरिक क्षमता है."

आरंभिक आनुवंशिक सर्वेक्षणों से विशेष कार्यक्रम के प्रतिभा खोजी अधिकारियों को किसी विशेष खेल में किसी विशेष खिलाड़ी की योग्यता तय करने में काफी सहायता मिली है. उत्तर-पूर्व राज्यों में सीधे मुकाबले वाले खेलों के उपनिदेशक एस.एस. राय (28) बताते हैं, "लाठीबाजी के खेल थांग-ता, कालारिप्पायत जैसे खेलों में तुरत-फुरत प्रतिक्रिया की जबरदस्त जरूरत रहती है. इसलिए लगता है कि इसके खिलाड़ी तलवारबाजी में भी कामयाब हो सकते हैं."

जिम्नास्टों के चुनाव की प्रक्रिया दिल्ली में आयोजित 'अपना उत्सव' के दौरान शुरू हुई थी. 9 से 13 साल की आयु की जिन 4 लड़कियों और एक लड़के को चुना गया वे इन दिनों नेहरू स्टेडियम में रहते हैं और प्रशिक्षण के लिए हर रोज इंदिरा गांधी स्टेडियम आते-जाते हैं. उनके लिए स्कूल की भी विशेष व्यवस्था की गई है और उनके परिवारों को हर माह 300 रु. भेजे जाते हैं ताकि परिवार को इनकी अनुपस्थिति के कारण आर्थिक हानि न उठानी पड़े. प्राधिकरण के सचिव एस.बासु (42) कहते हैं, "इन बच्चों से हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदकों की उम्मीद तो नहीं बांधे हुए हैं लेकिन जिम्नास्टिक तो एक आधारभूत खेल है जिसमें हमें हमें राष्ट्रीय स्तर सुधारना है."

खेल और युवा कल्याणमंत्री मार्गरेट अल्वा कहती हैं, "शुरू में खेल संघ मेरी जान के पीछे पड़े हुए थे पर अब वे मानने लगे हैं कि यह अच्छा कार्यक्रम है. इसे खास वर्गों तक सीमित नहीं रखना चाहिए"

हॉकी के लिए होनहार खिलाड़ियों का चुनाव भी काफी रोचक रहा है. बिहार के गुमला, सिंहभूमि और पलामू जिले, ओडीसा में सुंदरगढ़ तथा मध्य प्रदेश के रायगढ़ में बांस के जड़ से बनी स्टिक और गेंद से खेला जाने वाला खेल 'खसी' बहुत लोकप्रिय है. साल भर चलने वाली 'खसी' प्रतियोगिताओं में जीतने वाले को एक खसी (बकरी) और दूसरे नंबर की टीम को एक मुर्गा दिया जाता है. एसएजीपी के सहायक निदेशक नरसिंहा राव (38) ने 8 हफ्ते के भीतर मोटरसाइकिल पर 2000 किमी यात्रा करके 31 वनवासी क्षेत्रों में खसी टूर्नामेंट आयोजित किए. इस साल अप्रैल में गुमला में सबसे अच्छी टीमों के बीच टूर्नामेंट कराया गया जिसमें पूर्व ओलंपिक खिलाड़ी बलबीर सिंह तथा माइकल किंडो ने 42 होनहार लड़कों और 28 लड़कियों को विशेष प्रशिक्षण के लिए चुना. किंडो खुद भी वनवासी हैं और इसी इलाके से हैं.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तीरंदाज लिंबा राम, श्याम लाल और श्यामसुंदर रूसी कोच निकोलाइव के साथ

खिलाड़ियों के सही चुनाव और प्रशिक्षण के लिए एसएजीपी वैज्ञानिक तरीके अपना रही है. पिछले पखवाड़े 30 फुटबाल खिलाड़ियों और 70 हॉकी खिलाड़ियों की गति और शारीरिक सहनशक्ति की जांच करने के लिए विभिन्न तरह के परीक्षणों का आयोजन किया गया. 30 मीटर की तेज दौड़ के बाद खिलाड़ियों की धड़कन मापी गई. 6 छोटी दूरी की दौड़ के बाद एसएजीपी के खेल चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर विपिन भल्ला (36) ने खिलाड़ियों के रक्त की जांच की. इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के जांच काउंटर ने 40 सेकेंड में ही बता दिया कि अमुक खिलाड़ी इतनी गति से दौड़ सकता है.

उत्साह से भरे 14 वर्षीय हॉकी खिलाड़ी बेंजामिन एक्का का कहना था, "इन मशीनों के आंकड़ों से हमें तुरंत पता चल जाता है कि कौन खिलाड़ी दूसरों से बेहतर है." और भल्ला कहते हैं, "हमारे यहां खेल चिकित्सा फिलहाल आरंभिक दौर में है. यदि कोच गंभीर हों तो इन आंकड़ों का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है."

वनवासी इलाकों से आए तीरंदाज लिंबा राम और श्यामलाल की चमत्कारी सफलता ने कार्यक्रम में नई जान फूंक दी. इन खिलाड़ियों ने बता दिया कि तीरंदाजी तकनीकी मामला है जो मांसपेशियों के नियंत्रण और मानसिक स्थिति पर निर्भर है

एसएजीपी की आरंभिक सफलता ने पुराने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को काफी उत्साहित किया है. एशियाड में लंबी कूद का पदक जीतने वाले और अब कोच की भूमिका निभा रहे सुरेश बाबू की टिप्पणी थी, "खुशी की बात है कि पुराने ढर्रे को इस कार्यक्रम ने उलट दिया है. खिलाड़ियों की सही शारीरिक क्षमता पता लगने से उन्हें सही तकनीकें सिखाई जा सकती हैं." वे इन दिनों बंगलूर में उन भारतीय महिला एथलीटों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के इंचार्ज हैं जिन्हें सिओल ओलंपिक में भाग लेना है.

दूसरी सरकारी योजनाओं के मुकाबले इस कार्यक्रम की खूबी यह है कि इसमें खिलाड़ियों की स्कूली शिक्षा के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी उनका पूरा ध्यान रखा जाता है. पदक जीतने की संभावना के अलावा इस कार्यक्रम के अंतर्गत मिलने वाले भोजन, कपड़े और शिक्षा ने भी प्रशिक्षणार्थियों को आकर्षित किया है.

एथलेटिक्स विभाग की मुखिया और लंबी दूरी की धाविका रह चुकी रचना गोविल बताती हैं कि सिर्फ खिलाड़ियों के चुनाव में स्थानीय प्रशासन की काफी मदद लेनी पड़ी. उनके अनुसार, "खिलाड़ियों के माता-पिता उन्हें भेजना नहीं चाहते थे क्योंकि ये बच्चे उनके लिए कमाई का साधन थे. पर जब प्रशिक्षणार्थियों का पहला दल छुट्टियों में अपने गांव में जाता है और अपने अनुभवों के बारे में लोगों को बताता है तब दूसरे परिवार भी आकर मांग करते हैं कि उनके बच्चों को भी कार्यक्रम में शामिल कर लिया जाए."

देश में ठीक ढंग से सीखे हुए प्रशिक्षकों की कमी के कारण कार्यक्रम में विदेशी प्रशिक्षकों को भी शामिल करने का फैसला किया गया. तीरंदाजी और पानी के खेलों के लिए रूस से एलेक्जेंडर निकोलाइव और और एलेक्जेंडर गुस्कीं को बुलाया गया. तीन महीने प्रशिक्षण देने के बाद गुस्कीं लौट गए हैं. उम्मीद है कि इस साल के अंत तक वे दो साल के नए अनुबंध पर कार्यक्रम में फिर से शामिल हो जाएंगे. फुटबाल के क्षेत्र में अंजन चौधरी (30) पश्चिमी जर्मनी से 'फूसडाल लेरेर' की डिग्री लेकर आए हैं जो वहां सर्वोच्च प्रशिक्षण डिग्री मानी जाती है. यह डिग्री पाने वाले वे पहले गैर-यूरोपियन हैं.

अधिकांश भारतीय प्रशिक्षक खेल चिकित्सा विशेषज्ञों के सुझाए परीक्षणों के प्रति बहुत उत्सुक नहीं हैं. पर यह तय है कि एथलेटिक्स में खिलाड़ी की क्षमताओं को छोटे-छोटे परीक्षणों से बहुत सटीक नापा जा सकता है. उदाहरण के लिए 30 मीटर की तेज दौड़ से खिलाड़ी की प्राकृतिक क्षमता और गति; खड़ी कूद से टांगों की शक्ति; सिर के ऊपर से शॉटपुट फेंकने से शरीर की कुल शक्ति; 600 मीटर दौड़ से गति और 1500 मीटर दौड़ से सहनशक्ति का अनुमान लगाया जा सकता है. एथलेटिक्स प्रशिक्षक पी.वी.वी. रावणन कहते हैं, "परीक्षणों से टीक और प्लाइवुड का अंतर पता लग जाता है. माल की ताकत इस पर निर्भर है कि वह किस लकड़ी का है."

स्तर के मामले में समझौता न करने का दावा करते हुए बसु कहते हैं, "हमारा इरादा देश भर में कई खेलों में राष्ट्रीय प्रतिभा भंडार तैयार करना है. इसलिए शरीर की गतियों में वैज्ञानिक नियमों का उपयोग करना ही विशेष कार्यक्रम का मूल सिद्धांत है."

अलेप्पी केंद्र में नौकायन के प्रशिक्षणार्थी सुबह 4 से 5 घंटे तक पानी में रहकर प्रशिक्षण लेते हैं और दोपहर बाद वे अपने मल्टी-जिम्नेजियम में अभ्यास करते हैं. बंगलूर के कांतीर्वा स्टेडियम में लंबी दौड़ के सिद्दी प्रशिक्षणार्थी हर रोज लंबी दूरी की दौड़ नहीं लगाते. प्रशिक्षण की एकरसता से बचने के लिए वे बास्केटबाल भी खेलते हैं. 40 वर्षीय प्रशिक्षक पुरुषोत्तम राय की मान्यता है, "युवकों की एथलेटिक योग्यताओं के विकास के लिए उन्हें एक से अधिक क्षेत्र में करतब दिखाने का अवसर दिया जाना चाहिए." एसएजीपी के प्रबंधक इस कार्यक्रम में मनोवैज्ञानिकों को भी शामिल कर रहे हैं जिससे

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

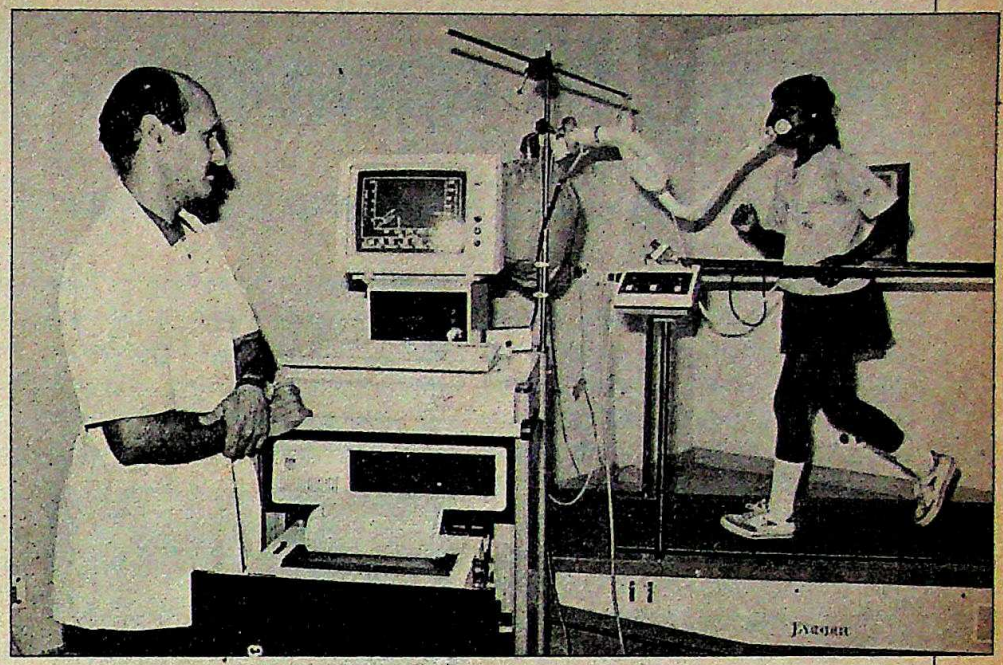

फेफड़ों के आक्सीजन खींचने की क्षमता की जांच

बेहतर नतीजे पाने के मकसद से खिलाड़ियों की गति और सहनशक्ति की जांच कई तरह के परीक्षणों से की जाती है. और फिर उनकी साप्ताहिक प्रगति के आंकड़े विश्लेषण के लिए खेल प्राधिकरण के कंप्यूटर में पहुंचा दिए जाते हैं

प्रशिक्षणार्थियों को ध्यान केंद्रित करने, मन से डर हटाने और प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने का अवसर मिले.

कार्यक्रम को काफी लचीला और खुला बनाया गया है. दो सिद्दी युवकों को एथलेटिक के लिए बुलाया गया था लेकिन जब उन्होंने कुश्ती का बेहतर प्रदर्शन किया तो उन्हें कुश्ती प्रशिक्षण के लिए दिल्ली भेज दिया गया. कोई और सरकारी योजना होती तो चोट खाए खिलाड़ियों को प्रशिक्षण से बाहर कर दिया गया होता लेकिन कोया जनजाति के 23 वर्षीय एम. बुल्ली को इलाज और हल्की सर्जरी के बाद फिर से तीरंदाजी प्रशिक्षण में शामिल कर लिया गया.

यात्रा भत्ते जैसे मामलों तक में नियम लचीले रखे गए हैं. अधिकारियों ने राय को अनुमति दे दी कि वे सिद्दी लड़के-लड़कियों की यात्रा भत्ते को उनके खाते में जमा करवा दें ताकि जब वे क्रिसमस की छुट्टियों में घर जाएं तब परिवार वालों के लिए उपहार खरीदकर ले जाएं. इसी तरह पुन्नामादा झील में अभ्यास करने वाले नौकायन प्रशिक्षणार्थियों को होस्टल से आने-जाने के लिए नई साइकिलें दी गईं.

इन नीतियों का न केवल आयोजकों ने बल्कि प्रशिक्षणार्थियों ने भी स्वागत किया. वैली स्कूल वेलूर के दसवीं कक्षा के छात्र और बाधा दौड़ के प्रशिक्षणार्थी फरहा महमूद का कहना था, "शुरू में कंतीर्वा स्टेडियम में सिद्दी खिलाड़ियों के साथ मेलजोल बढ़ाने वालों की संख्या कम थी. कुछ लोग तो नाराज थे कि विशेष रियायतें दी जा रही हैं. लेकिन अब लगता है कि ऐसा करना वाजिब ही है. इससे हमारे खेल का दर्जा सुधरेगा." 18 वर्षीय अनपढ़ सिद्दी एथलीट फ्रांसिस सालु इससे पहले जानवर चराया करता था. अब वह लंबी दौड़ में केरल का प्रतिनिधित्व करने की उम्मीद लगाए हुए है. कर्नाटक के मध्यम दूरी धावक रेलवे क्लर्क वी. सत्यनारायणा (21) कहते हैं, "यह कार्यक्रम तो बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था."

खेल कार्यक्रम के बारे में जो एकमात्र शिकायत सुनी जाती है वह यह है कि यह दूसरे लोगों के लिए नहीं है. तीरंदाज संजीव सिंह कहते हैं, "मेरे माता-पिता के पास काफी पैसा है और मैं इस खेल में बने रहना चाहता हूं. ऐसे अच्छे तीरंदाजों की भी कमी नहीं जो शिकारी समाजों से नहीं हैं. लेकिन उनकी ओर कोई ध्यान नहीं देता."

यह कार्यक्रम स्पष्ट रूप से उन वर्गों तक केंद्रित है जिन्हें खेलों में अवसर नहीं मिलता. अल्वा कहती हैं, "शुरू में तो खेल संघ मेरी जान के पीछे पड़े हुए थे पर अब वे मानने लगे हैं कि यह अच्छा कार्यक्रम है और सरकार को इसे केवल उन वर्गों तक सीमित नहीं रखना चाहिए जिनमें किसी विशेष खेल की प्राकृतिक प्रतिभा है."

कार्यक्रम के नतीजे अब धीरे-धीरे सामने आ रहे हैं. अपनी रिकार्ड तोड़ उपलब्धियों के कारण शामलाल और लिंबा राम के नाम तीरंदाजी प्रेमियों की जुबान पर चढ़ चुके हैं. लेकिन अभी ऐसे कई और नाम चमकने बाकी हैं. बी. श्यामसुंदर (23), स्कालांग दोरजी (19) और फुंसोक आंगचुक (21) अगले दो सालों में ही एशियाई तीरंदाजी में करतब दिखाने जा रहे हैं. एक चप्पू वाली नौकायन में वी.एस. साजी (19) और टी.ए. कुरीयाकोस (21) डोंगी चालन में वी.एस. मैथ्यू (17) और अनिल कपूर (18) से भी चमत्कार की उम्मीद है. गुस्र्की को पूरा भरोसा है कि जोरदार अभ्यास और यूरोप में कुछ अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के अनुभव के बाद ही वे भारत को नौकायन के क्षेत्र में एशियाई सिरमौर बना देंगे.

नाम कमाने की क्षमता रखने वाले दूसरे खिलाड़ियों में 17 वर्षीय एग्नेल जर्मी भी हैं जिनमें एक बेहतर डिकेथलीट (दस खेलों में पारंगत) बनने की भरपूर संभावनाएं हैं. जर्मी कहते हैं, "भाला फेंकना तो मुश्किल है लेकिन चक्का फेंकने में बहुत मजा आता है." चार महीनें के भीतर ही जर्मी का थ्रो 31.74 मीटर से बढ़कर 40.16 मीटर हो चुका है. इसी तरह 31 वर्षीय मैरी साहिर को 800 मीटर और 1500 मीटर दौड़ में विशिष्टता हासिल करने की उम्मीद है. दिल्ली राज्य चैंपियनशिप में एक स्वर्ण, चार रजत और एक कांस्य पदक जीतने वाली रश्मि दास (10) का भविष्य भी उज्वलन दिखता है.

इन सफलताओं के बावजूद विशिष्ट खेल कार्यक्रम के अधिकारी फूंक-फूंककर कदम रख रहे हैं. राव चेतावनी भरे शब्दों में कहते हैं, "वर्तमान कार्यक्रम को ठोस आधार दिए बिना इसका विस्तार करना नुकसानदेह हो सकता है." कार्यक्रम पर 1986-87 में 40 लाख रु., 1987-88 में 55 लाख रु. और इस साल 80 लाख रु. खर्च होने की उम्मीद है. अधिकांश पैसा केंद्रों के निर्माण और खेल उपकरणों पर खर्च किया जा रहा है. फिलहाल कार्यक्रम की केवल नींव ही रखी जा रही है. पर अब तक की उपलब्धियों को देखते हुए भारतीय खेल क्षेत्र में इसे एक प्रभावशाली लंबी छलांग माना जाएगा.

—अमरनाथ के. मेनन बंगलूर, हैदराबाद, दिल्ली और अलेप्पी में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बिहार

मिथिला में 'महाभारत'

ललित नारायण मिथिला वि.वि. के कुलपति का अनूठा अभियान

राज्य के मंत्री की प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति में रोक लगाना, मंत्री के बेटे की विश्वविद्यालय में दादागीरी पर अंकुश लगाना, विश्वविद्यालय के 38 प्रोफेसरों की पदावनति करके रीडर बना देना, इंकाई राजनैतिक खेमेबाजी में लगे आध्यापकों और विश्वविद्यालय कर्मचारियों को दुरुस्त करना. यह सारा चमत्कार बिहार के किसी विश्वविद्यालय का कोई कुलपति कर डाले तो है न अचंभे की बात. मगर उत्तर बिहार के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के आठवें कुलपति डॉ. शकीलुर रहमान ने यह कर दिखाया है. तभी तो विश्वविद्यालय के छात्र, अध्यापक और अभिभावक उन्हें आठवां 'अवतार' कहते हैं और भ्रष्टाचार व खेमेबाजी के खिलाफ उनकी जंग को 'महाभारत' बहरहाल इस महाभारत की चर्चा खास तौर से इसलिए हो रही है कि डॉ. रहमान ने उस हस्ती—नागेंद्र झा—को चुनौती दी है जो विश्वविद्यालय की राजनीति के बूते आज राज्य के मानव संसाधन विकास मंत्री के ओहदे तक पहुंच गई है.

रहमान कहते हैं, "मंत्री से मेरा कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है. पर कुलपति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि विश्वविद्यालय को भ्रष्टाचार और खेमेबाजी के माहौल से निजात दिलवाऊं ताकि पढ़ाई-लिखाई का माहौल बने."

1972 में कायम हुआ यह विश्वविद्यालय वैसे तो देश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है जिससे 67 कॉलेज जुड़े हुए हैं, लेकिन विडंबना यह है कि इसे अभी तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मान्यता नहीं दी है. दरभंगा में स्थापना के बाद ही विश्वविद्यालय मैथिल ब्राह्मण नेताओं नागेंद्र झा और पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र की राजनैतिक अखाड़ेबाजी का अड्डा बन गया.

रहमान ने यहां पदभार संभालने के बाद पाया कि ज्यादातर अध्यापक और कर्मचारी इन्हीं नेताओं की कृपा से बहाल हुए हैं और उनके 'राजनैतिक एजेंट' की तरह काम करते हैं. और तो और, उन्होंने पिछले कुलपति को अजूबे समझौतों के लिए मजबूर कर दिया, मसलन यह कि उन्हें हर पांच साल बाद तरक्की मिलनी चाहिए. इस समय 64 कर्मचारी डिप्टी रजिस्ट्रार के वेतनमान पर काम कर रहे हैं. जरूरत से कहीं ज्यादा कर्मचारी व शिक्षक हैं. विश्वविद्यालय ओवरड्राफ्ट के भरोसे चल रहा है.

फोटो: कृष्ण मुरारी किशन

झा (बाएं) और रहमान: घमासान की तैयारी

कुलपति डॉ. रहमान ने नागेंद्र झा को चुनौती दी है जो विश्वविद्यालय की राजनीति के बूते ही आज मंत्री बन गए हैं

शिक्षा जगत का खास तजुर्बा रखने वाले रहमान इन तथ्यों से चकरा गए और हालात सुधारने की ठान ली. उन्हें लग गया कि नागेंद्र झा से दो-दो हाथ किए बगैर मामला सुलटने वाला नहीं है. उन्होंने कुलाधिपति (राज्यपाल) को पांच पेज की चिट्ठी लिखी जिसमें विश्वविद्यालय की तमाम बुराइयों, राजनैतिक दखल और विश्वविद्यालय के सुधार के उपायों का जिक्र किया. रहमान ने पाया कि विश्वविद्यालय के अध्यापक झा एक अरसे से काम पर नहीं आए हैं और उन्होंने छुट्टी भी नहीं ली है. इसलिए रहमान ने प्रोफेसर के पद पर झा की तरक्की रोक दी. रहमान कहते हैं, "मैंने मंत्री की तरक्की तकनीकी आधार पर रोकी है." झा के समर्थक कहते हैं कि झा ने प्रधानाचार्य की छुट्टी की अर्जी भेजी थी जिन्होंने शायद उसे आगे विश्वविद्यालय के दफ्तर को नहीं भेजा.

रहमान यहीं नहीं रुके. उन्होंने अध्यापकों की तरक्की के बाकी सारे मामले की भी समीक्षा की. 38 को इसके नाकाबिल पाया और पदावनत कर दिया. इन लोगों में झा के दायां हाथ माने-जाने वाले नीलांबर चौधरी भी हैं. रहमान ने शिक्षकों व कर्मचारियों के फर्जी भत्ते भी रोक दिए जिससे 75 लाख रुपए सालाना की बचत हुई. इन कार्रवाइयों से शिक्षक व कर्मचारी भड़क उठे और हड़ताल कर दी तो रहमान ने छह कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया. और तो और, झा के बेटे संजय झा की, जो मेडिकल के अंतिम वर्ष का परीक्षार्थी है, दादागीरी खत्म कर दी.

जब मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद नागेंद्र झा के घर एक दावत में आए तो उनके समर्थकों ने मुख्यमंत्री के आगे सारा किस्सा बयान किया. सूत्रों के अनुसार उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि उन लोगों की पूरी राजनीति विश्वविद्यालय के इर्द-गिर्द ही घूमती रही है, और रहमान इसी को बरबाद करने पर तुले हैं. ऐसे में तो मिथिलांचल से इंका का सफाया ही हो जाएगा. मुख्यमंत्री ने इस पर क्या कहा यह अभी पता नहीं चला.

लेकिन झा इस बात से हमेशा इनकार करते रहे हैं कि वे विश्वविद्यालय की गंदी राजनीति में शामिल हैं. और उधर रहमान भी अड़े हैं, "सरकार चाहे तो मुझे बरखास्त कर दे. पर मैं परिसर का माहौल ठीक करने की कोशिश करता रहूंगा." इस बीच छात्रों और आम लोगों की एक बड़ी तादाद रहमान के समर्थन में खड़ी हो गई है. अब इस 'महाभारत' का फैसला इस पर निर्भर करेगा कि 'कृष्ण' (मुख्यमंत्री) किसका साथ देते हैं.

—फरजंद अहमद

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नाटक

आदिम जीवन की विडंबना

आदिवासियों के जीवन मूल्यों से छेड़छाड़ का गंभीर परिणाम

'हवाओं का विद्रोह'
नाटक
विभु कुमार
नेशनल पब्लिशिंग हाउस, 23, दरियागंज, नई दिल्ली
कीमत: 24.00 रु.

'आदिवासी' शब्द सुनते ही जिज्ञासाओं की एक लंबी कतार लग जाती है. आदिम जन-जीवन को लेकर विभिन्न प्रकार की अवधारणाएं, प्रचारात्मक साहित्य के जरिये धकेला गया 'ज्ञान' पाठक, दर्शक या श्रोता के लिए एक स्वादिष्ट डिश की भूमिका का पर्याय बन जाता है. आधुनिक, सभ्य, वैज्ञानिक, शिक्षित या ऐसे ही किसी समाज में रहते हुए, इसी 'सामाजिक आंख' से जब एक आदिवासी का जीवन परखा जाता है तो ऐसा लगता है मानो इन्हें जीवन से बरखास्तगी मिली हुई है. 'हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए' का सा भाव भी एकाएक इन सामाजिकों के मन में कौंधने लगता है.

मगर समाजशास्त्र की पवित्र भावनाओं का सम्मान करते हुए विचार करें तो यह बात सामने आती है कि आदिम जन-जीवन को तथाकथित सभ्य बनाने की फिराक में पड़कर उस जीवन का अनादर अधिक किया जाता है, सम्मान कम. जीवन को अत्यधिक शांत, प्राकृत, सुविधा-विहीन तथा एकदम लोक मुहावरे में एक खास स्तर पर जीते हुए इन आदिवासियों में शिक्षा, राजनीति, आधुनिकता वगैरह को इंजेक्ट करना कितना खतरनाक (भी) साबित हो सकता है, इस बात को समर्थ युवा नाटककार विभु कुमार ने अपने नाटक 'हवाओं का विद्रोह' में, एक बार फिर से तथा सशक्त स्वर में उठाने का भरपूर प्रयास किया है.

इस नाटक में छिंदवाड़ा जिले के तामिया ब्लॉक में पड़ने वाले पातालकोट को बतौर पृष्ठभूमि इस्तेमाल किया गया है. आदिम जन-जीवन के तरीके से पलती लक्ष्मी पातालकोट से बाहर आकर एक शिक्षा आश्रम में पढ़ाई करती है, शिक्षित, सुसभ्य तथा विशालतर समाज में वह धीरे-धीरे रम जाती है और छुट्टियों में गांव वापस लौटने पर उसे यकीन ही नहीं हो पाता कि उसने अपना बचपन इसी गांव-घर में गुजारा है. पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद गांव के ठीक-ठाक युवक से उसकी शादी कर दी जाती है. लक्ष्मी की कोशिश होती है कि पति के साथ शहर चलकर रहे ताकि उनके "बच्चे क्यों इस गंदे और गरीबी से भरे वातावरण में रहें? कम-से-कम, उन्हें तो नई दुनिया, नई रोशनी मिले. तरक्की के लिए सही वातावरण मिले." मगर स्थितियां निरंतर विघ्नकारी होती जाती है और अंततः लक्ष्मी आत्महत्या कर लेती है. लक्ष्मी की आत्महत्या के बाद पूरी घाटी के लोग इकट्ठा होते हैं, संभवतः यह फैसला करने के लिए कि आगे से किसी को भी शिक्षा के लिए न उकसाया जाए ताकि लक्ष्मी की आत्महत्या के साये के पैर दुबारा उस घाटी में पड़ने न पाएं.

"... हम चाहते हैं कि वे राष्ट्रीय धारा से जुड़ें. इससे बड़ा मजाक और क्या होगा? हमारे लिए तो आदिवासी का मतलब है एक नंग-धड़ंग आदमी, जो हाथ में तीर-कमान लिये है. और उसके उस नंगेपन का चटखारा लेने हम जाते हैं"
'हवा का विद्रोह' से एक संवाद

पुरुष-एक के पात्र के रूप में सूत्रधार के माध्यम से यह नाटक प्रमुखतः बुना गया है. पुरातन आदिवासी मूल्य तथा आधुनिक सुधार और संस्कृति के प्रदर्शक कुछ सरकारी हथकंडों के बीच का द्वंद्व पिता, लक्ष्मी, मां, सरिता, सास तथा दूसरे पात्रों के माध्यम से यहां उकेरा गया है. नाटक की कथा को मुख्य गति लक्ष्मी के आत्मालाप से या फिर सूत्रधार के हस्तक्षेप से मिलती है. कहीं-कहीं संवादों की प्रखरता बढ़ जाती है और इसी विचारोत्तेजन की स्थिति में नाटक की सार्थकता भी. उदाहरणार्थ, संवाद की एक झलक यहां देखी जा सकती है:

"कितनी अजीब बात है कि आदिवासी हमारे यहां दर्शनीय चीज हैं—हमारे अपने जीवन के अंग नहीं!"

"तब भी हम चाहते हैं कि वे राष्ट्रीय धारा से जुड़े, इससे बड़ा मजाक और क्या होगा? हमारे लिए तो आदिवासी का मतलब है—एक नंग धंड़ग आदमी, जो हाथ में तीर-कमान लिए है और उसके उस नंगेपन का चटखारा लेने हम जाते हैं."

इसके अतिरिक्त एक आदिवासी लोक-गीत भी इस नाटक का आकर्षक अंग है जो खास तरह से इसमें स्थानीयता पिरो देता है.

वस्तुतः यह नाटक आदिवासियों की जीवन शैली और जीवन स्तर को उन्नत बनाने के रास्ते में पैदा हुई गड़बड़ियों को सामने लाने का प्रयास है. नाटक का आशय है कि तथाकथित उन्नत समाज आदिवासियों के हितार्थ काम तो करे मगर उनकी वास्तविक नस्ल, सभ्यता एवं संस्कृति और सामाज के स्वरूप में कोई हस्तक्षेप न करे. ऐसा करने का एक ही अर्थ होगा—उन्हें गुलामी या आत्महत्या की तरफ धकेलना!

इस नाटक की थीम बेहद सशक्त है मगर मंच की दृष्टि से बेहद किताबी और शाब्दिक. लक्ष्मी की टूटन, खीझ, प्रताड़ित होने का प्रक्रम तथा आत्महत्या तक पहुंच जाने का अनिवार्यतम प्रोसेस गायब है. दृश्यों में भी अत्यधिक पैच हैं जिससे यह वन-पीस नाटक नहीं बन सका है. सूत्रधार अर्थात् पुरुष—एक की ईमानदार भूमिका तक भी कभी मन पर हावी नहीं हो पाती और न ही लक्ष्मी के प्रति कोई धांसू सहानुभूति जुट पाती है. ऐसा प्रतीत होता है मानो नाटक लिखने के मोल-तोल में यह नाटक लिख भर दिया गया हो, इसे धैर्य से जिया नहीं गया. यह अधैर्य केवल संवादों में ही नहीं दृश्यों तक में परिलक्षित होता है क्योंकि एक दृश्य तो बाकायदा स्वतंत्र रूप से दोबारा रख दिया गया है. लगता है कि इस नाटक को मंच पर खेलना किसी भी निर्देशक के लिए चुनौती नहीं, एक 'चूं-चूं का मुरब्बा मार्के वाली पहेली को सुलझाने जैसा जटिल काम है. हिंदी साहित्य में तो वैसे भी अच्छे आधुनिक नाटकों की बेहद कमी है और यदि विभु कुमार भी इस दिशा में कुछ नहीं कर पाते तो निश्चित ही यह हिंदी नाट्य समाज के लिए दुखद खबर है.

—राजकुमार गौतम

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कविता संग्रह

यथार्थ का निषेधपूर्ण चित्रण

आक्रोश और आत्मघाती विस्फोट की अराजक कविताएं

इस अकाल वेला में
(राजकमल चौधरी की कविताएं)
संपादक: सुरेश शर्मा
वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली
कीमत: 95 रुपए

राजकमल चौधरी की प्रकाशित, अप्रकाशित सभी कविताएं इस संकलन में हैं. जो कविताएं किन्हीं कारणों से छूट गई हैं उन्हें अगले संस्करण में शामिल करने का संपादक का वायदा है. राजकमल चौधरी बिटनीकों से प्रभावित एक औघड़ कवि थे जिनका महज 38 वर्ष की आयु में ही निधन हो गया था. लेकिन उनकी खास तरह की कविताओं ने उस समय लोगों का ध्यान खींचा था.

गहरे जड़ जमाए सामाजिक और राजनैतिक तनावों से ग्रस्त व्यवस्था के प्रति आक्रोश और विरक्ति का भाव, दबाव के असहय क्षणों में आत्मघाती और अराजक रूप में एक विस्फोट की तरह फूट निकलता है. उसमें कोई दृष्टि या दिशा नहीं होती. संवेदना, शिल्प और संप्रेषण का त्रिकोण गायब रहता है. काव्यानुभूति संदर्भों की समुचित नियोजना से पुष्ट न होकर इकहरी और विपर्यस्त होती है. राजकमल की कविताओं का संसार इन्हीं विशेषताओं अथवा न्यूनताओं से निर्मित होता है. उनकी कविताएं अंतर्दृष्टि के अभाव में दिशाहीन, इसी तरह के अराजक, आक्रोशपूर्ण, गुस्सैल और आत्मघाती विस्फोट की कविताएं हैं जो जीवन के प्रति स्वीकार और आस्था का नहीं, निषेध का भाव लिए हैं. "आदमी को इस लोकतंत्री संसार से अलग हो जाना चाहिए/ चले जाना चाहिए कस्साबों गांजाखोर साधुओं/भिखमंगों अफीमची रंडियों की काली और अंधी दुनिया में/मसानों में अधजली लाशें नोचकर/खाते रहना श्रेयस्कर है जीवित पड़ोसियों को खा जाने से/हम लोगों को अब शामिल नहीं रहना है/इस धरती के आदमी को हमेशा के लिए खत्म कर देने की/साजिश में!"

नई कविता के अनंतर अकविता, भूखी पीढ़ी, विद्रोही पीढ़ी, बिटनीक पीढ़ी कई क्षणभंगुर काव्यांदोलनों ने अपनी झलक दिखाई थी. यह मोहभंग, गहरी हताशा और निराशा से उपजी कविता थी जिसे मोटे रूप में अकविता का आंदोलन कहा गया. दूसरी ओर एक राह धूमिल की थी जिसे प्रत्यक्ष कथन की कविता कहा गया. इन दोनों के ही तत्व राजकमल की कविता में मिलते हैं: "नहीं जानता था आदिम पिता—/कि जिसे थोड़े दैहिक परिवर्तन के साथ आत्मवत पाकर/प्रतियोगी समझकर, पराजितकर, मल्लयुद्ध में जिसके/कोमल उरोजों को अपने कठोर वक्ष से कुचलकर,—वह/काट-पीट-घोंटकर मार डालना चाहता था/उसी मादा देह से अपने नर-शरीर का—/उत्तेजित, स्वयंस्फूर्त पौरुष भी संघर्षण करने लगेगा/जानता नहीं था/कि स्वतः उद्रिक्त एक अंग देह-विवर में पत्थर के भाले-सा धंस जाएगा." और फिर "भाषा अब वेश्या है. सबकी बांहों में/समाई हुई सबके ओंठों पर बसी रहती है/उसके विवस्म अंगों में अब कोई अर्थ नहीं."

> **"अगली दुनिया के अन्वेषकों,/ हमारी दुनिया तो यही है/ प्रभुता से नियंत्रित दासता से अभिशप्त/बर्बर अमानवीय ताकतों से अनुशासित/अनियामक जनता की दुनिया इसे तोड़ो..."**
>
> इसी संग्रह से

पहले उद्धरण में अकवितावादियों और नीचे के उद्धरण में धूमिल की कविताओं का तत्व मौजूद हैं. इस लिहाज से काव्यांदोलनों के औपचारिक इतिहास में एक महत्व राजकमल का है. उनके महत्व का एक बिंदु यह भी है कि उनकी कविता समग्र रूप से परिवेश, परिस्थितियों और व्यवस्था की जकड़ और दबाव की शिला के नीचे परास्त और विकृत हुई काव्यानुभूति का प्रमाण देती है. समकालीन परिस्थितिक (सिचुएशनल) वास्तविकताओं का स्फूर्त और प्रामाणिक उभार उनकी कविताओं में बराबर मिलता है: "कि झलक उठे-निरंतर नंगी पीठें/झुकी पीठों/हजारों-लाखों-करोड़ों पीठों से/उतारे-चढ़ाए-निकाले जाते बोरे अनाज के! /पीठ और पेट एक हो चुके हैं/ जिनके/गोलघर के बाहर/गोल चक्कर में/ अनाज उनकी पीठ से पेट तक नहीं पहुंचता."

अगर वास्तविकताओं के इन उभारों को दिशा भी मिल जाती तो उनकी कविता ताकतवर और सृजनात्मक हो जाती—मुक्तिबोध की तरह. लेकिन कवि सीमा में बद्ध है: "स्थान, काल-पात्र की शारीरिक स्थितियों का/अगर शीलभंग करती है मेरी कविता/उसे अब और कुछ नहीं करना चाहिए." अधिकांश कविताएं संप्रेषण की समस्या से अछूती हैं. कवि अपने संवेदनों को सार्वजनीन बनाने के धैर्य और प्रक्रिया का निर्वाह नहीं कर पाता. फिर भी संकलन में सधे हाथ और मानसिकता की कविताएं हैं: "अब तो सागर तल में होगा खंड-खंड जलयान/सच कहता हूं/उस पागल भाटे में वापस आना/वापस लाना/उस पार चले जाने से/दुष्कर था!..."

'मुक्ति प्रसंग' और 'दास कविता' संकलन में सशक्त और महत्वपूर्ण कविताएं हैं. मृत्यु से कुछ समय पूर्व कवि ने अपने को बदला था, जिसकी प्रतीति 'इस अकाल वेला में' कविता में होती है. संपादक ने कवि के बदलाव के प्रति उन्मुख एक वक्तव्य का हवाला संकलन की भूमिका में दिया है जिसमें वह "जनता के पास लौटकर" परिवर्तन की आकांक्षा से परिचालित होना चाहता है. लेकिन उसके तत्काल बाद कवि की अकाल मृत्यु ने उस बदलाव को फलीभूत नहीं होने दिया.

फिर भी यथार्थ के चित्रण और कहीं-कहीं स्वीकार के लिए इन कविताओं का महत्व अक्षुण है: "अगली दुनिया के अन्वेषकों/हमारी दुनिया तो यही है/प्रभुता से नियंत्रित/दासता से अभिशप्त/ बर्बर अमानवीय ताकतों से अनुशासित/ अनियामक जनता की दुनिया/इसे तोड़ो/जो शोषित रहकर भी/शास्ता और शासक के अटूट संबंध की/मूलभूत चक्राकार अवस्थिति की/चाहे अनचाहे जाने अनजाने/ पोसती और पालती है."

—प्रेम सिंह

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सभी फोटो: भवान सिंह

मेघालय

मोर्चे पर मर्द

मातृसत्ता को गंभीर चुनौती

मातृसत्ता के दिन अब गिने-चुने रह गए हैं. पर्वतीय राज्य मेघालय में पुरुष अपने अधिकारों के लिए उठ खड़े हुए हैं. खासी, गारो और जैंतिया वनवासियों (जो राज्य की 79 फीसदी आबादी हैं) की सदियों पुरानी मातृसत्तात्मक व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठने लगी है.

अभी तक मेघालय में महिलाओं की ही तूती बोलती रही है. वंश परंपरा उन्हीं के नाम से चलती है (पिता के नाम से नहीं) और वे ही पारिवारिक संपत्ति की संरक्षक हैं. पैतृक संपत्ति आम तौर पर सबसे छोटी बेटी को सौंपी जाती है. इसके पीछे तर्क यह है कि वह ज्यादा देर तक अपने मां-बाप के यहां रहेगी. पर बड़ी बेटी को भी शादी के बाद घर बसाने के लिए कुछ जायदाद दी जाती है. उनके पति भी वहीं आकर रहते हैं.

मगर महिलाओं पर जिम्मेदारियों का पहाड़ रहता है. वे न सिर्फ परिवार के लिए रोटी जुटाती हैं बल्कि बाल-बच्चे भी पालती हैं और घर के बाकी कामकाज भी करती हैं. पुरुषों के पास वक्त फालतू होने के कारण उनमें से ज्यादातर नशा करते हैं और जुआ खेलते रहते हैं. सिर्फ राजनीति और धार्मिक रीति-रिवाज के मामले में ही उनका दब-दबा होता है.

लेकिन पुरुषों को अपनी मां के परिवार में काफी सम्मान मिलता है और कमाने-धमाने वाला लड़का अपनी तनख्वाह भी मां को ही सौंपता है. कबीलाई कानून के मुताबिक पुरुष को उत्तराधिकार का कोई अधिकार नहीं. अगर किसी को अपनी मां से तोहफे में कुछ पैसा या जमीन मिल भी गई तो उसकी मौत के बाद वह सब उसकी बहन या मां के परिवार को मिल जाता है.

पर कई मां-बाप अब धीरे-धीरे सोचने लगे हैं कि उनके बेटे भी जायदाद के उतने ही हकदार हैं जितनी उनकी बेटियां. इसके अलावा बहुत से नौजवान नाम के आगे अपनी मां का उपनाम लगाने से परहेज करने लगे हैं और अब कुछ ही पुरुष अपनी तनख्वाह मां को सौंपते हैं.

कुछ साल पहले तो ऐसा सोचा भी नहीं जाता था. पर आज शिलंग के व्यापारी पी. साइमलेह ने अपनी जायदाद अपने 11 बच्चों में बराबर-बराबर बांटने के मामले में कबीले की ओर से विरोध पर काबू पा लिया है. उनका कहना है, "हम अपने बेटों से भेदभाव क्यों करते रहें?" उधर परिवहन और संचारमंत्री अमिसन मरक को अपनी जायदाद पांच बेटों और एक बेटी में बांटने का फैसला करते समय जरा भी सोचना-समझना नहीं पड़ा.

पिछले साल राज्य सरकार द्वारा 'स्वअर्जित संपत्ति कानून' पास करने के बाद ही लोगों के लिए कबीलाई कानूनों से भिड़ना मुमकिन हो सका. इस कानून के तहत कोई भी जैसे चाहे अपनी संपत्ति का बंटवारा कर सकता है. अब जायदाद के सैकड़ों मामले अदालतों और गांव पंचायतों में दायर होने लगे हैं.

उत्तर-पूर्व पर्वतीय विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र की शिक्षक सुजाता मिरी का तर्क है कि यह तो होना ही था क्योंकि "वनवासी पुरुष ने अपनी नई छवि बना ली है और वह समाज से अपना जायज हक पाने के लिए जागरूक हो गया है." लेकिन खासी विद्वान आर.टी. रिबिया का मत इसके विपरीत है, "जायदाद पर बेटी काबिज रहे तो बढ़िया सामाजिक नियंत्रण रहता है पर अब परिवार का हर सदस्य व्यक्तिगत संपत्ति का लालच पाल बैठा है."

स्वीटीपाई (बाएं); और कामकाजी खासी महिलाएं: परिवार का बोझ

यह बदलाव पश्चिमीकरण और बाकी भारत के पुरुषप्रधान समाज के संपर्क में आने का अपरिहार्य नतीजा है. करीब 55 फीसदी वनवासी ईसाई हैं. समाजशास्त्री महेंद्र नारायण कर्ण कहते हैं, "ईसाई अब उन अंतर्विरोधों को समझने लगे हैं जो पितृसत्तात्मक मूल्यों पर आधारित धर्म को मानने और मातृसत्तात्मक समाज में रहने की वजह से पैदा हुए हैं."

समाजशास्त्री मानते हैं कि वनवासी पुरुष इसलिए ज्यादा कुशलता से काम नहीं करते क्योंकि वे हीन भावना से ग्रस्त हैं. खासी परिवारों में मां-बाप और बच्चों के रिश्तों का अध्ययन करने पर क्यानसे वरज्री ने पाया कि वहां लड़कों को कम दुलार मिलता है. पढ़ाई और पहनावे के मामले में उन्हें कम तरजीह दी जाती है. चूंकि मां-बाप बेटियों की ही हौसलाअफजाई करते हैं इसलिए लड़कों में महत्वाकांक्षा का अभाव है. वरज्री कहते हैं, "लड़के खुद को असुरक्षित पाते हैं क्योंकि वे अनचाहा होने का भाव लिए बड़े होते हैं. आज के दौर में वे शरणार्थी की तरह नहीं जी सकते."

महिलाएं भी इस नजरिये से सहमत हैं. एक महिला व्यापारी स्वीटीपाई साइमलेह कहती हैं, "लड़के इसलिए गैरजिम्मेदार हैं क्योंकि सामाजिक व्यवस्था उनके खिलाफ है. वे सोचते हैं कि जब वे जमीन-जायदाद नहीं हासिल कर सकते तो मेहनत से क्या फायदा." पर मेघालय के पुरुष कुछ हिम्मत दिखाएं तभी वे यह सब बदल पाने में कामयाब हो पाएंगे.

—रमेश मेनन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तंजावुर

लुप्त होता अनूठापन

परंपरागत हिंदू बस्तियों में मुस्लिम आबादी की रिहाइश बढ़ी

तमिलनाडु के तंजावुर जिले के तिरुनागेश्वरम शहर में शिव मंदिर के ठीक बगल वाली शिवन सन्निधि स्ट्रीट में 25 ब्राह्मण परिवार दशकों से रहते थे. धार्मिक माहौल से ओत-प्रोत दिखती थी यह गली. जो कायापलट हो रहा है उसका जीता-जागता उदाहरण है शिवन सन्निधि गली. राज्य भर के 34,000 मंदिरों और तीर्थ-स्थलों में से करीब आधे इसी जिले में हैं. लेकिन आज तंजावुर के मंदिरों के आसपास

सभी चित्र : श्याम टेकवानी

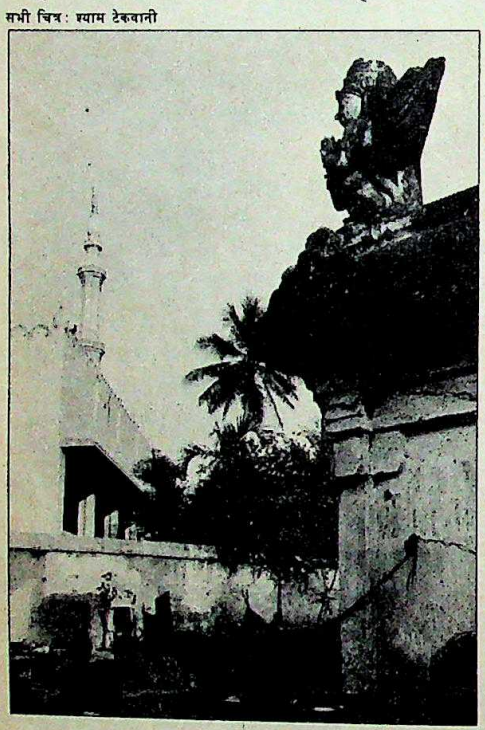

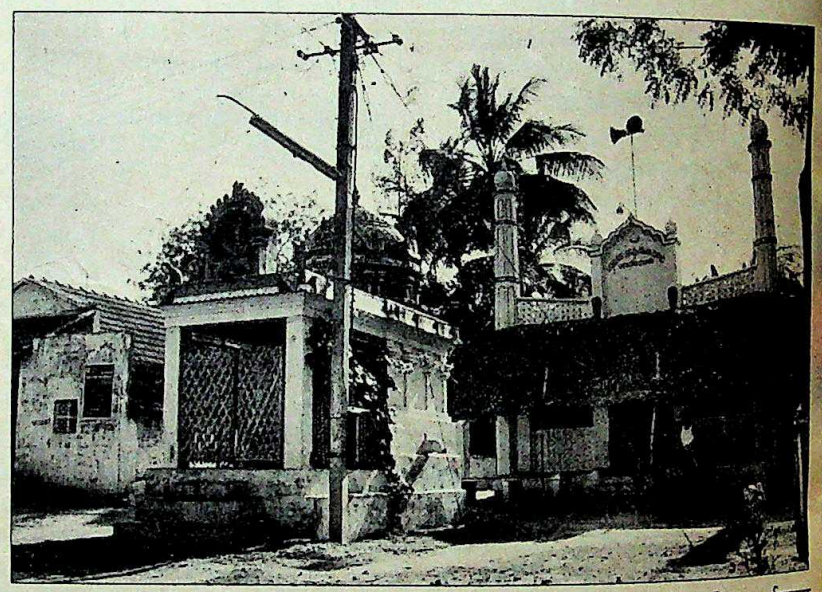

अय्यमपेट में मंदिर और मस्जिद आमने-सामने (ऊपर); और अवूर का कायापलट (बाएं)

बरामदों पर बैठे दिखते थे धोती पहने, खुली छाती पर जनेऊ लटकाए ब्राह्मण, तो घरों में आती-जाती महिलाएं नौ गज की साड़ी में लिपटीं. लेकिन आज इस गली का रंग-रूप ही बदलता जा रहा है. वेस्ती (धोती) की जगह अब लुंगी ज्यादा दिखने लगी है. यानी मुसलमानों की संख्या बढ़ती जा रही है.

अभी छह महीने पहले 31 वर्षीय अब्बास जकारिया ने 47 वर्षीय के. सुब्रमणिया अय्यर का घर खरीदा है और सपरिवार इसमें रहने लगे हैं. इससे कुछ दिन पहले इसी शहर के बिना मोहम्मद, जो मलेशिया में कारोबार करते हैं, इसी गली में आए थे. अय्यर कहते हैं, "आज इसी गली के 25 घरों में से 10 में मुसलमान रहते हैं."

कभी तंजावुर जिले (जनसंख्या: 4.5 लाख) का दैनंदिन जीवन यहां के मंदिरों के इर्दगिर्द ही घूमता रहता था. लेकिन अब यहां बेला-चमेली और भस्मों की सुगंध नहीं, मसालेदार मुस्लिम व्यंजनों की खुशबू फैली रहती है. मंदिर परिसर के पवित्र स्थलों के आगे साष्टांग दंडवत करती महिलाओं की जगह अब अग्रहारम (मंदिर के आसपास ब्राह्मणों के घरों का समूह) के अधखुले दरवाजों से बुर्कानशीं औरतें ही झांकती दिखती हैं. कोलम (घर के द्वार पर चावल के आटे से बनी अल्पना) की जगह अब दरवाजे के ऊपर चांद-तारे बने दिखते हैं.

यह बदलाव सीधे-सीधे अर्थशास्त्र का ही खेल है. तंजावुर का औसत मुसलमान परिवार यहां के हिंदू परिवार से अधिक कमाता है. इसका कारण यह है कि जिले के प्रायः हर ग्रामीण मुस्लिम परिवार का कोई न कोई सदस्य किसी पश्चिम एशियाई देश या सिंगापुर या मलेशिया में नौकरी कर रहा है. दूसरा कारण यह है कि ज्यादातर खेतिहर मजदूर माकपा या भाकपा के झंडे तले संगठित हो गए हैं और ज्यादा मजदूरी लेने लगे हैं. जमींदार ब्राह्मणों के लिए खेती अब मुनाफे का धंधा नहीं रहा. अय्यर कुछ नाराजगी से कहते हैं, "जो जमीन को जोते-बोए, वो जमीन का मालिक होए नारे के कारण हमें अब पैदावार का आधा हिस्सा ही मिल पाता है. और फिर हम मजदूरों की मर्जी के बिना जमीन बेच भी नहीं सकते." इस झमेले के कारण आज कई जमींदार अपनी जमीन बेचकर शहरों की ओर रुख करते जा रहे हैं.

एक मोटे अनुमान के अनुसार 80 फीसदी अग्रहारमों में अब मुसलमान आ बसे हैं. इसी प्रकार कंबाकोणम शहर के प्रसिद्ध सर्वमान्य अग्रहारम के सभी 60 घर मुसलमानों के हाथों में जा चुके हैं. विडंबना यह है कि ये सभी घर 16वीं शताब्दी में एक बादशाह ने ब्राह्मणों को उपहारस्वरूप दिए थे. आज इस बदले हुए समय का रोना रो रहा है अग्रहारम के ठीक आगे बना अगोरा वीरभद्र स्वामी मंदिर. यह एकदम उपेक्षित हो गया है. कभी धार्मिक गतिविधियों का केंद्र रहा यह मंदिर आज चांद-सितारे अंकित दरवाजों वाले हरे रंग के घरों के बीच एकदम अटपटा लगता है.

कुंबाकोणम शहर के पेरुमल मंदिर से लगे इरुमैक्करा अग्रहारम के एक हिस्से और रागोजापंडितर स्ट्रीट में भी ऐसा ही बदलाव नजर आता है. पांच साल पहले तक यहां के सभी 32 घर हिंदुओं के थे. पर आज इस गली में 17 मुस्लिम परिवार आ गए हैं. इसी गली के 70 वर्षीय महादेव अय्यर कहते हैं, "मुसलमान धीरे-धीरे इन अग्रहारमों से ब्राह्मणों को बाहर करते जा रहे हैं."

इस उलटफेर के कारण इस राज्य के परंपरागत हिंदू स्थलों में अब मस्जिद

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ड्यूराटफ इनक़लाब।

क्या आप खुश नहीं कि यह इनक़लाब आपके दौर में आया?

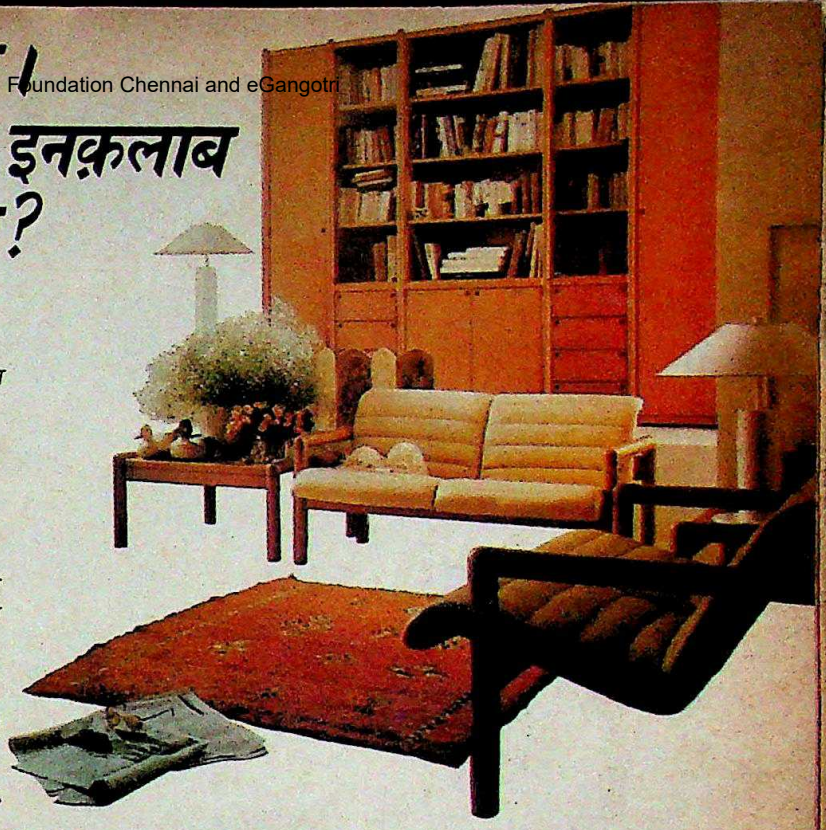

यह है ड्यूराटफ का इनक़लाब : ड्यूराटफ—एक बहु-उपयोगी बोर्ड, जो वर्षों से विदेशी घरों का नकशा बदलता आ रहा है। अब आपके घर को भी शानदार नया रूप देकर आपको आश्चर्यचकित कर देगा। कम्प्यूटर प्रोसेस्ड टेक्नोलॉजी के जरिये तैयार किया गया ड्यूराटफ, प्लाइवुड और पार्टिकल बोर्डों से कहीं बेहतर है।

इस बोर्ड से हर काम आसान : ड्यूराटफ में शानदार जिन्दगी गुजारना बिलकुल आसान। यह विभिन्न किस्मों के प्री-लैमिनेटेड खूबसूरत डिजाइनों में मिलते हैं जो आपकी मज़बूत सतह को लम्बे अरसे तक आकर्षक बनाये रखेंगे। आप अपने डाइनिंग टेबल को ही लीजिये, इस पर कोई भी चीज़ काटिये-छाँटिये और अगर गरम सूप भी गिर जाये तो भी ड्यूराटफ पर कोई असर नहीं पड़ता। इसे दीमक से बचाने की कोई ज़रूरत नहीं। यह नमी का असर नहीं लेता जैसे फूलना या खपच्चियाँ आदि उतरना।

जैसा जी चाहे इस्तेमाल कीजिये : खुदाईवाली नकशेदार कुर्सी या स्कैण्डिनेवियन टेबल, दीवार का पैनेल, किताबों की ताक या जो जी चाहे बनायें। लैमिनेटेड या प्लेन, ड्यूराटफ अधिक मज़बूत, दोनों ओर चिकनी सतह और एक जैसी मोटाई। कांटी या स्क्रू लगायें, एधेसिव की ज़रूरत नहीं।

आपके पैसों की सही कीमत चुकाने वाला बोर्ड : ड्यूराटफ अब आपको मामूली कीमत पर देगा लकड़ी का विलासपूर्ण काम। क्योंकि, ड्यूराटफ लकड़ी के काम को आसान बनाकर आपके पैसों की भारी बचत करता है और वक्त भी बचाता है। उदाहरणस्वरूप, ड्यूराटफ में कीमती एज बैंडिंग या लिपिंग की ज़रूरत नहीं होती। अन्य बोर्डों की तरह ड्यूराटफ के ग्रेन पर कटाई करने से यह चटखता नहीं।

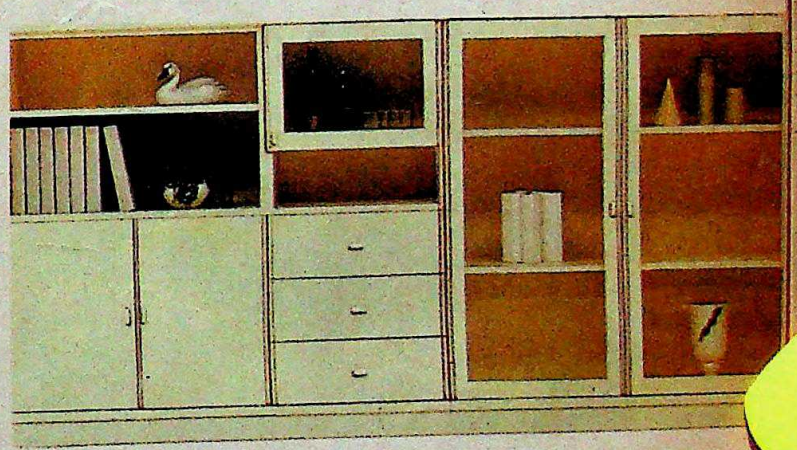

ड्यूराटफ की नई दुनिया में कदम रखिये—यह आसान और व्यावहारिक है। इसमें आप आराम व शानदार जिन्दगी जी सकेंगे। सचमुच, ड्यूराटफ आपके ज़माने का एक ज़बरदस्त इनक़लाब है!

DURATUFF
टिकाऊ और मज़बूत बोर्ड

देखिये इसे, चीज़ें बनती हैं कैसे

HTA 3257

पूरा पुस्तिका के लिये लिखिये :
[illegible] टिम्बर प्रोडक्टस् लि.
[illegible] इंडिया एक्सचेंज प्लेस, तीसरी मंज़िल
[illegible] ७०० ००१.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पंखों पे चली आएं...ताज़ी ठंडी हवाएं!

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

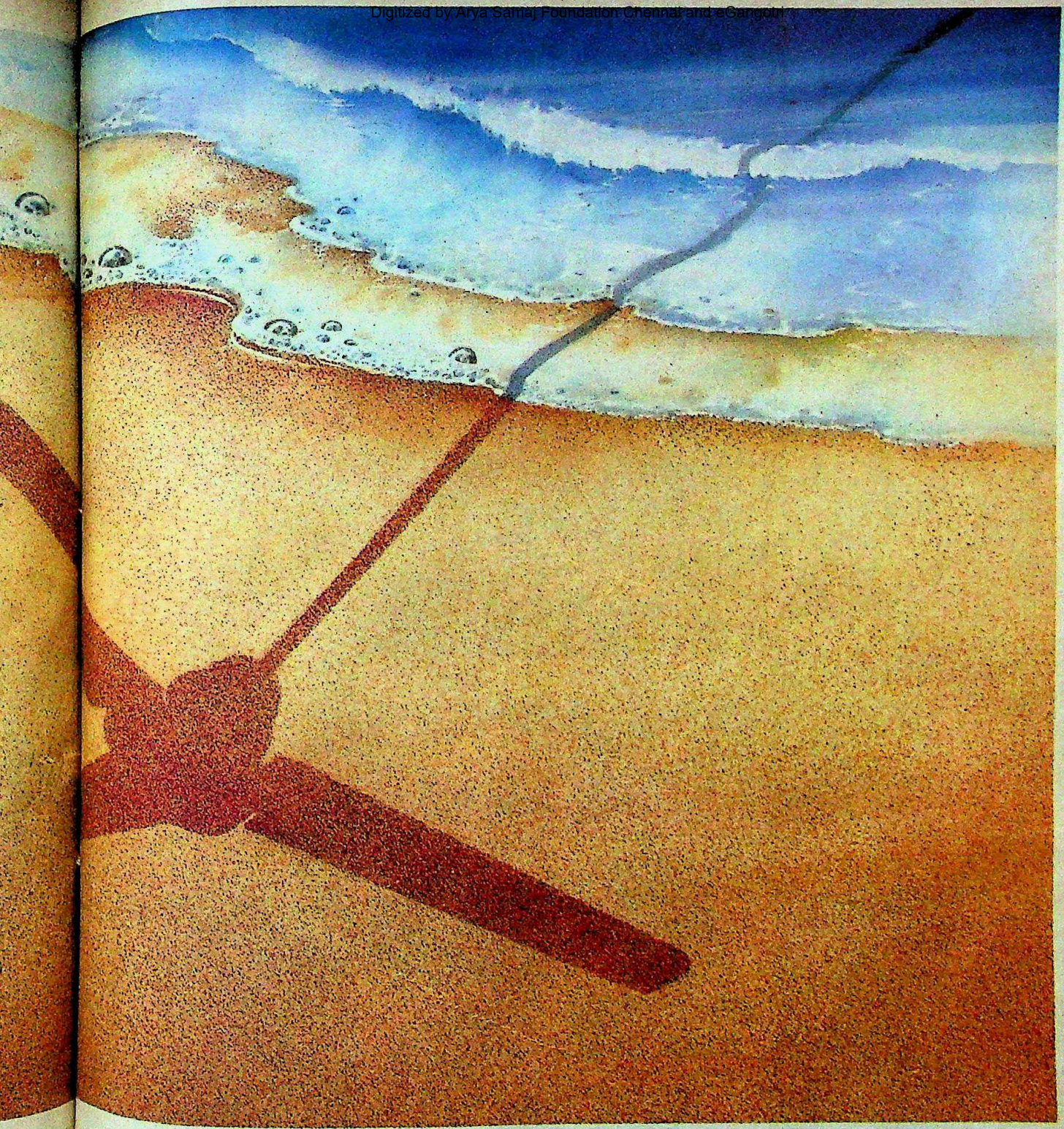

ओरिएन्ट फैन्स
ये ताज़ी हवाएं, जीवनभर आपकी हो जाएं.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सिन्टेक्स - वक्त की कसौटी पर अव्वल, एकमात्र विश्वसनीय रेडीमेड पानी की टंकिया

सिन्टेक्स ने एक दशक से भी ज्यादा समय से सभी तरह की आबोहवाओं का सामना करके अपनी गुणवत्ता को साबित कर दिखलाया है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कोहिमा तक, पानी के संग्रह एवं परिवहन के सभी उपयोगोंमें चल रही, लाखों सिन्टेक्स की टंकिया, अब दिन ब दिन और भी लोकप्रिय होती जा रही है।

कम्प्यूटर की सहायता से चलने वाले आधुनिक मशीनों पर अनोखे मोल्डींग प्रोसेस से बनी –सिन्टेक्स पानी की टंकियों के लाभ भी अद्वितीय है।

* वजन में हल्की * लगाने में आसान * मजबूत एवं टिकाऊ * देखभाल से मुक्त * १०० % लीकप्रूफ एवं रस्टप्रूफ * बहुत ही आरोग्यप्रद * १०० लिटर से २०,००० लिटर की विविध साईजों एवं आकारों में उपलब्ध * बिक्री उपरांत सेवा भारत में सर्वत्र.

अधिक जानकारी के लिये संपर्क करें :

सिन्टर प्लास्ट कंटेनर्स

प्लास्टिक्स डिव्हीजन : दि भारत विजय मिल्स लि. कलोल (उ. गुजरात) ३८२ ७२१ (भारत) दूरध्वनी: (०२७६४) २२२८, २२७४ २३५२, ३१४४, ३१४५. तार : 'SINTEX', टेलेक्स :०१२१/७२९६ BVM IN.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

सिन्टेक्स - दुनियाकी नं. १ प्लास्टिक पानी की टंकिय

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

होने लगे हैं. अवूर का छोटा, प्राचीन कर्पागा विनयागर मंदिर भव्य, विशालकाय दारेस्सलाम मस्जिद के आगे निस्तेज-सा दिखने लगा है. और अब तो यह गली भी मुस्लिम गली के नाम से जानी जाने लगी है.

पापनाशम तालुके के अय्यमपेट में अब जीर्णावस्था में पहुंच चुके द्रौपदी अम्मा मंदिर के पीछे चमकदार नया मस्जिद बन गया है. मंदिर के पास रहने वाला 35 वर्षीय नाई टी. जयरामन कहता है, "अय्यमपेट में आज बहुत ही कम हिंदू रह गए हैं, इसलिए अधिक चढ़ावा नहीं मिलता. और फिर मंदिर की देखभाल करने का बहुत उत्साह भी नहीं रह गया है." धीरे-धीरे उपेक्षित हो जाने वाला एक और मंदिर है अय्यमपेट के पास के चक्रपल्ली का चक्रवागेश्वर मंदिर. यहां से हिंदुओं के चले जाने के कारण मंदिर में घास उग आई है. रोज सुबह इस ऐतिहासिक मंदिर में नाम की पूजा ही होती है.

पिछले में तंजावुर के इन उपेक्षित मंदिरों का वार्षिकोत्सव मनाना पुरोहितों को मुश्किल लगने लगा है. भक्तों की संख्या में कमी के कारण चढ़ावा भी कम चढ़ता है. अग्रहारम का माहौल एकदम बदल जाने की बात मुसलमान भी स्वीकार करते हैं. मंदिर के पास रहने वाले कपड़ा व्यापारी मोहम्मद फारूक सिराजुद्दीन कहते हैं, "इन जगहों का पूरा हिंदू माहौल ही गायब हो गया है. अब तो हर घर में आपको सिर्फ मुसलमान ही मिलेंगे."

लेकिन सुखद बात यह है कि इस बदलाव के कारण हिंदू और मुसलमानों के रिश्तों में बहुत तनाव नहीं पैदा हुआ है. तिरुनागेश्वरम की शिवन सन्निधि स्ट्रीट में रहने वाले 50 वर्षीय एस. इब्राहिम ने बताया, "शिव मंदिर के पास बसना शुरू में कुछ अटपटा तो जरूर लगा लेकिन अग्रहारम के अपने ब्राह्मण पड़ोसियों से हमें कोई परेशानी नहीं हुई. हम अपना जीवन जीते हैं, ब्राह्मण अपना."

लेकिन अंदरूनी सांप्रदायिक तनाव के कुछ छोटे-मोटे उदाहरण भी हैं. जब से विश्व हिंदू परिषद ने प्राचीन कर्पागा विनयागर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया है, तब से दोनों संप्रदायों के रिश्ते पहले जितने सहज नहीं रह गए हैं. जो हिंदू अपना घर बेचकर जा रहे हैं उनकी मुख्य चिंता पैसा है. वे मंदिरों को लेकर बहुत चिंतित नहीं हैं.

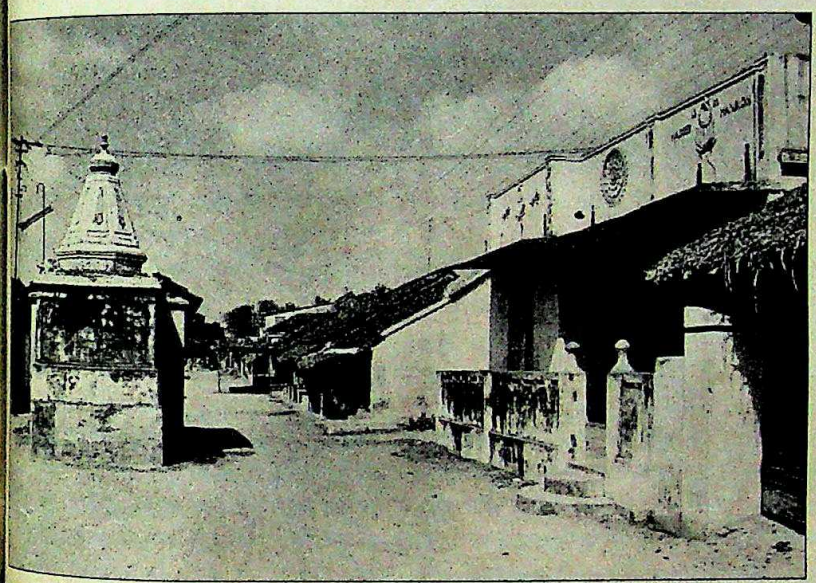

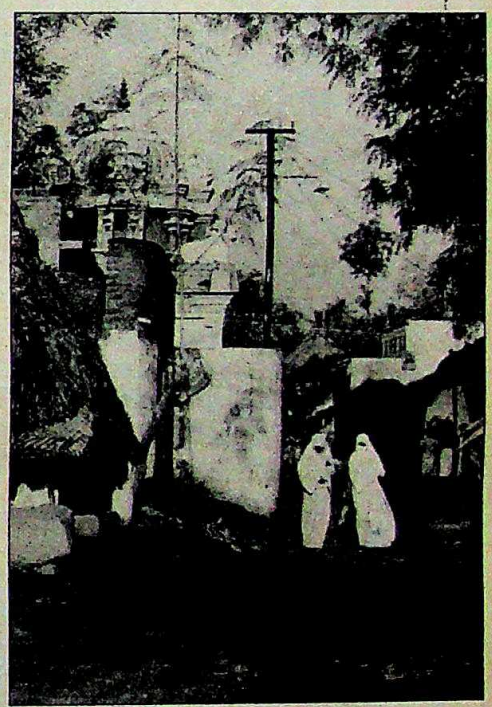

मुस्लिम स्ट्रीट में खस्ताहाल मंदिर (ऊपर); और मंदिर के सामने से गुजरतीं बुर्कानशीं महिलाएं (दाएं)

बड़े शहरों में काम करने वाले अपने बाल-बच्चों के साथ रहने को उत्सुक बुजुर्ग हिंदुओं के घर भी मुसलमान लोग खरीद रहे हैं. नन्निलम तालुके के तेधियुर अग्रहारम में वी. कृष्णमूर्ति ने दस वर्ष पहले एक घर 30,000 रुपए में खरीदा था. पांच साल पहले उन्होंने इस घर को 10 गुनी ऊंची कीमत पर एक मुसलमान के हाथों बेच दिया. फिर वे तंजावुर शहर में अपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बेटे के साथ रहने चले गए. तंजावुर जिला विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष एस.एम. स्वामीनाथन कहते हैं, "मुख्यतः आर्थिक कारणों से ही हिंदू लोग मंदिरों के पास के अपने घर बेच रहे हैं."

तंजावुर के ग्रामीण इलाकों से हटने वाले हिंदू अपनी संपत्ति मुसलमानों को इसलिए बेचना पसंद करते हैं, क्योंकि वे ऊंची कीमत देते हैं. कुंबाकोणम तालुके के नचियारकोइल में एक बरतन की दुकान में काम करने वाले 68 वर्षीय राजमणि अय्यर कहते हैं, "मुसलमान हिंदुओं के मुकाबले किसी भी घर के लिए 25 से 100 फीसदी तक अधिक कीमत देने को तैयार रहते हैं."

मजेदार बात यह है कि अग्रहारम या पुरानी हिंदू बस्तियों में आने वाले मुसलमान कहीं बाहर के न होकर तंजावुर जिले के ग्रामीण इलाकों के ही हैं. उनके पूर्वज यहां 18वीं शताब्दी में मुगल शासन के समय आए थे. आंकड़ों के अनुसार आज राज्य की 5.5 करोड़ आबादी में मुसलमानों की आबादी 4.7 फीसदी ही है. तंजावुर जिले में दो दशक पहले की .सात फीसदी की तुलना में अब उनकी आबादी नौ फीसदी है.

अनेक मुसलमान परिवार अपनी बदलती जरूरतों के लिए ही जायदाद खरीद रहे हैं. जैसे जकारिया कुंबाकोणम में अपनी पैतृक संपत्ति में बंटवारे के बाद कहीं और जाने को मजबूर हो गए. उन्हें बंटवारे में पैसा मिला लेकिन रहने की जगह नहीं मिली. सो उन्होंने शिवन सन्निधि स्ट्रीट में घर खरीदा. फिर, बाशा को अपनी पारिवारिक जमीन पर विवाद के कारण अवूर का अपना पुराना घर छोड़ना पड़ा और उन्होंने कर्पागा विनयागर मंदिर के पास घर खरीदा.

इस खरीद-फरोख्त और आबादी की अदला-बदली के पीछे कारण चाहे जो भी हो, एक बात स्पष्ट है कि तंजावुर का अनूठापन लुप्त होता जा रहा है.

—एस.एच. वेंकटरमनी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विकलांगों का थिएटर

सच का नाटकीय असर

सीमाओं में बंधी एक विशाल दुनिया

'अनजान' का एक दृश्यः आंखमिचौनी

यह एक अनूठा रंगमंचीय अनुभव था—दर्शकों के लिए भी और कलाकारों के लिए भी. रोजमर्रा की जिंदगी में पहनी जाने वाली निकर, पैंट और कमीजों में सजे 12 अभिनेता अर्धगोलाकार कतार में बैठे हैं, टटोल-टटोलकर एक हाथ से दूसरे हाथ में जाने वाला माइक्रोफोन मंच पर लगातार चलता रहता है. हर बदलते हाथ और चेहरे के साथ माइक्रोफोन के रास्ते चलते हुए डायलाग दर्शक के कानों तक पहुंचते हैं और फिर अचानक ही शब्द पिघले शीशे का रूप ले लेते हैं. बहता हुआ गरम लावा दर्शक के दिल तक टीसदार लकीर खींचता चला जाता है.

एक के बाद एक डायलाग और दर्शक का दिल चटखने लगता है. नाटक खत्म होते-होते दर्शक की भीतरी आंखें जिंदगी के उस सच को साक्षात देखने लगती हैं जिसे उसकी बाहरी आंखें अपनी हर रोज की जिंदगी में देखकर भी नहीं देख पातीं.

जाने-माने रंगकर्मी बैरी जान के निर्देशन में तैयार किए गए और थिएटर एक्शन ग्रुप तथा 'वेरी स्पेशल आर्ट्स इंडिया' के साझे तत्वाधान में खेले गए नाटक 'जिंदगी' की असली ताकत यह है कि यह महज एक नाटक नहीं बल्कि हकीकत है. यह नेत्रहीन किशोर अभिनेताओं की अपनी-अपनी असली कहानी है जिसे उन्होंने बचपन से लेकर अब तक अपने मन से देखा और तन से भोगा है. हर अभिनेता रटे-रटाए डायलाग बोलने के बजाय अपने ही शब्दों में आपबीती बयान करता है. यही कारण है कि हर मंचन के दौरान इस नाटक के डायलाग बदलते रहते हैं.

हसनपुर से दिल्ली के एक अंध विद्यालय में आए किशोर तेजबीर सिंह 14 का डायलागः "जब मैं छोटा था तब मैं देख सकता था. मेरी मां मुझे तैयार करके रोज स्कूल भेजती और मैं गांव के लड़कों के साथ खेलने निकल जाता. हम चोरी से आम तोड़ते और खूब खेलते. दोपहर बाद घर आकर हम गाय-भैंस चराने के लिए जंगल चले जाते और वहां नहर के पुल से कूद-कूदकर पानी में आंखमिचौनी खेलते.... पर अब तो पूरी जिंदगी ही आंखमिचौनी का खेल होकर रह गई है."

'जिंदगी' के अलावा नेत्रहीन किशोरों ने एक और नाटक 'अनजान', मानसिक रूप से अशक्त बच्चों ने 'जैसा भी तैसा' और गूंगे-बहरे किशोरों ने 4 रोचक माइम का भी मंचन किया. 16 वर्षीया मूक-वधिर नर्तकी निरुपमा कौल तो लाजवाब थी. उसके नृत्य की खासियत यह है कि वह न सुन पाने की कमी को तबले पर थिरकती उंगलियों की लय पढ़कर पूरा कर लेती है और बीच-बीच में ताली बजाकर तबलावादक के साथ अपने पैरों की थिरकन का तारतम्य भी बांधती रहती है.

एक चौकीदार की हत्या के आसपास घूमने वाला नाटक "जैसा भी तैसा' जिस सादगी से पुलिस और न्यायपालिका का मजाक उड़ाता है वह मन को छू लेने वाला है. मानसिक कमजोरी वाले किशोरों द्वारा पेश किए गए इस नाटक में मजिस्ट्रेट जिस तुरत-फुरत अंदाज में अभियुक्तों को 14 साल, 12 साल और 'फांसी' का हुक्म सुनाता है और मुकदमा खत्म होने के बाद ही लाश उठाने की इजाजत दी जाती है वह न्याय व्यवस्था की हृदयहीनता को बहुत बेबाकी से बेनकाब करने वाला है. इस नाटक में बलवंत राय मेहता स्कूल के स्पास्टिक छात्र तपन उर्फ 'गब्बर सिंह' ने जिस आत्मविश्वास के साथ अपनी भूमिका निभाई है वह सिद्ध करता है कि स्पास्टिक व्यक्ति का शरीर भले ही अस्वस्थ हो पर उसका मस्तिष्क किसी सामान्य व्यक्ति के मुकाबले कम समर्थ नहीं होता.

इसी तरह गूंगे-बहरे किशोरों द्वारा पेश किए गए चारों माइम अभिनय की दृष्टि से इतने प्रभावी थे कि अनजान दर्शक उनमें से अधिकांश अभिनेताओं को व्यावसायिक अभिनेता मान बैठे. लेकिन वेरी स्पेशल आर्ट्स इंडिया की उपाध्यक्ष मोयना सिंह कहती हैं, "हमारा इरादा बच्चों को रंगमंच कलाकार बनाना नहीं बल्कि उन्हें इस सचाई का एहसास कराना है कि उनमें भी अपनी योग्यताएं हैं." यदि इस कार्यक्रम को इसी कसौटी परखा जाए तो मानना होगा कि कमानी रंगमंच पर उतरे कलाकार अपनी अक्षमताओं के बजाय अपनी योग्यताओं की ओर लोगों का ध्यान खींच पाने में पूरी तरह सफल रहे.

—विजय क्रांति

निरुपमा कौलः लय पर थाप

फोटोः स्टूडियो सबरवाल

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सभी फोटो: ऋतुराज द्विवेदी

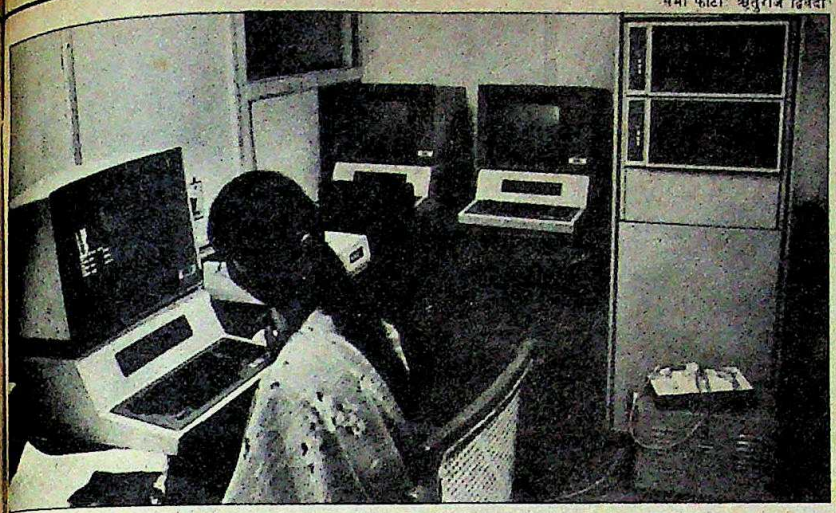

मध्य प्रदेश

कंप्यूटर पहुंचा गांव में

पूरे राज्य के भू-अभिलेखों को कंप्यूटर में भरने की योजना

श्रीलाल शुक्ल की बेजोड़ व्यंग्य रचना 'राग दरबारी' में एक पात्र है लंगड़. उसे तहसील दफ्तर से एक सरकारी दस्तावेज की नकल की जरूरत है पर वह क्लर्क में आमतौर पर दी जाने वाली 5 रुपए की रिश्वत नहीं देना चाहता. कागज के एक टुकड़े को पाने के लिए उसे अपनी जमीन, जायदाद सब कुछ बेच देना पड़ता है. आखिरकार उसकी मौत हो जाती है पर नकल हाथ नहीं लगती.

लेकिन मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के भैरोंपुर गांव के किसान मांगीलाल को अपने खेत का भू-अभिलेख लेने के लिए अब रिश्वत देने की जरूरत नहीं रही. तहसील दफ्तर में आए ज्यादा कार्यकुशल और किसी तरह की मांग न करने वाले नवागंतुक— कंप्यूटर— से वह यह दस्तावेज पा सकता है. हालांकि अभी इस गांव में न बिजली है, न सिंचाई के साधन और न ही खेती के आधुनिक यंत्र.

राज्य सरकार ने इस साल के शुरू में गांवों के भू-अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण शुरू किया है. भैरोंपुरा से इस योजना का श्रीगणेश हुआ. राज्य के प्राय: 3.66 करोड़ खसरा नंबरों और करीब 44 करोड़ आंकड़ों को कंप्यूटर में सुरक्षित रखने की योजना है. भू-अभिलेखायुक्त हृषिकेश मिश्र कहते हैं, "इस कठिन काम को हाथ में लेने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है."

मिश्र इस महीने मुरैना जिले से इसका आरंभ कर रहे हैं. इस जिले के मुख्यालय में कुल 24 कंप्यूटर लगाए गए हैं और 28 अफसर इनमें भरी जानेवाली सूचनाओं की देखरेख और जांच करेंगे. इन अधिकारियों को इस काम में छह महीने लगेंगे. यह काम पूरा करने के बाद 16 कंप्यूटरों को इसी काम के लिए दूसरे जिलों में ले जाया जाएगा. बाकी 8 कंप्यूटर मुरैना जिले में ही, हर तहसील के लिए एक-एक के हिसाब से रखे जाएंगे. इनसे हर साल भू-अभिलेखों का रिकार्ड पूरा करने में मदद मिलेगी और उनकी नकल भी ली जा सकेगी.

मिश्र: कठिन काम का जिम्मा

भू-अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण की योजना में 3.66 करोड़ खसरा नंबरों व 44 करोड़ आंकड़ों की कंप्यूटरबंदी होगी

मुरैना में आंकड़ों की कंप्यूटरबंदी

वैसे सिर्फ मुरैना परियोजना में ही 40 लाख रु. खर्च होंगे. लेकिन राज्य सरकार को इसकी चिंता नहीं क्योंकि योजना का सारा खर्च केंद्र सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय वहन कर रहा है. मंत्रालय पूरी व्यवस्था के आधुनिकीकरण पर दृढ़ है. पूरे राज्य के भू-अभिलेखों को कंप्यूटर में भरने पर करीब 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे. मिश्र कहते हैं, "फिर भी यह खर्च सार्थक होगा."

कंप्यूटर लाने के पीछे एक मुख्य उद्देश्य यह भी है कि मांगीलाल जैसे किसानों को उनके भू-अभिलेखों की नकल तुरंत मिल सके. जमीन पर अपने कानूनी हक जताने तथा कर्ज व सब्सिडी लेने के लिए किसानों को इन अभिलेखों की सख्त जरूरत पड़ती है. भू-अभिलेख के अतिरिक्त आयुक्त टीनू जोशी कहते हैं, "आपसी झगड़ों और मुकदमेबाजी के चलते देहाती जीवन की शांति भंग हो जाती है, इसका मूल कारण है भू-अभिलेखों को परिपूर्ण करने में बरती जाने वाली लापरवाही."

इस योजना में मीन-मेख निकालने वाले लोग भू-अभिलेख विभाग द्वारा आंकड़े इकट्ठे करने की सरकारी योजना पर ही उंगली उठाते हैं. उनका मानना है कि इस प्रक्रिया में काफी समय लगेगा. भू-अभिलेखायुक्त की परियोजना रिपोर्ट के अनुसार हर तहसील के लिए एक, यानी 290 कंप्यूटर खरीदे जाने के बाद भी राज्य के सभी भू-अभिलेखों के आंकड़े कंप्यूटर में भरने में करीब चार साल लग जाएंगे. ग्वालियर में एक कंप्यूटर कंसल्टेंसी फर्म के मालिक राजकुमार शर्मा कहते हैं, "आंकड़े भरने के लिए गैर-सरकारी एजेंसियों की सहायता लेना ही सबसे किफायती है."

लेकिन मिश्र इससे सहमत नहीं हैं. उनका मानना है कि भू-अभिलेखों के आंकड़ों की प्रविष्टि एक खास काम है और इसे उनके विभाग के कर्मचारी ही कर सकते हैं. वे कहते हैं, "हम इसे एकदम मुकम्मल करना चाहते हैं." मुरैना परियोजना से ही यह मुद्दा तय होगा. कुछ भी हो, पर मध्य प्रदेश की बैलगाड़ी छाप अर्थव्यवस्था अब कंप्यूटर ढोने के लिए तैयार हो चुकी है.

—नरेंद्र कुमार सिंह, ग्वालियर में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उत्तर प्रदेश

गांवों को निगलते शहर

किसान अपनी जमीन सेंत-मेंत में देने को तैयार नहीं

उत्तर प्रदेश में गांवों को लीलते शहर सुरसा के मुंह की तरह बढ़ रहे हैं. किसानों के घरों-खेतों को निगलते हुए शहरों का विस्तार हो रहा है. पर किसान अब जमीन के लिए शहरों की अंतहीन क्षुधा से बिफर उठे हैं. उनमें अपनी जमीन का वाजिब मोल मांगने का संकल्प दिन-ब-दिन मजबूत होता जा रहा है.

राज्य के इन फैलते हुए शहरों और कस्बों के आसपास के कई गांवों में ग्रामीणों ने सरकारी एजेंसियों को अपनी जमीन पर कब्जा करने से रोक दिया है. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये सरकारी एजेंसियां उनकी जमीन की कीमत बहुत कम आंक रही हैं.

जमीन के लिए शहरों की न मिटने वाली भूख से किसान अब नाराज हो उठे हैं और बेहतर मोल मांग रहे हैं

आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं. सरकार की आवास व विकास एजेंसियों पर 13 लाख किसानों का 550 करोड़ रुपए बकाया है. यह रकम 1985 से अब तक सरकारी एजेंसियों द्वारा हथियाई गई किसानों की 1.5 लाख एकड़ जमीन की कीमत है (इससे पहले के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं).

सबसे बड़े देनदार उत्तर प्रदेश आवास और विकास बोर्ड को ग्रामीणों के 96 करोड़ रुपए देने हैं. इसके बाद नबंर आता है लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) का. उसने 65 करोड़ रुपए के बिलों का भुगतान नहीं किया है. इस फेहरिस्त में मेरठ, गोरखपुर, वाराणसी, आगरा, इलाहाबाद और बिजनौर समेत 13 दूसरे शहरों के विकास प्राधिकरण भी हैं. हरेक पर गांव वालों का 20 से 50 करोड़ रुपए बकाया है.

किसान कहते हैं कि अगर जमीन का मुआवजा बाजार दर पर तय किया जाए तो बकाया राशि इससे दस गुना ज्यादा होगी. अपने तर्क के हक में वे भूमि अधिग्रहण अधिनियम में 1984 में केंद्र सरकार द्वारा किए गए संशोधन का हवाला देते हैं. इस संशोधन के मुताबिक मुआवजा बाजार दर पर ही तय होना चाहिए, साथ ही जमीन के अधिग्रहण के तुरंत बाद उसका 80 फीसदी जिला कलेक्टर के पास जमा करा दिया जाना चाहिए. पर आवास एजेंसियों ने मानो कानून की धज्जियां उड़ाने की कसम खाई हैं.

इसलिए राजस्व विभाग ने पिछले साल मार्च में एक नया आदेश निकाला. इस आदेश के मुताबिक जिस जमीन का अधिग्रहण किया जाना है उस पर स्टांप ड्यूटी दर से कम मुआवजा नहीं दिया जा सकता. इसके साथ ही आवास परिषद और विकास प्राधिकरणों पर समूची बकाया रकम का भुगतान किए बगैर और जमीन का अधिग्रहण करने के लिए रोक लगा दी गई. पर इस आदेश का असर केंद्रीय संशोधन से कोई बहुत ज्यादा नहीं हुआ. आवास एजेंसियों ने भूमि अधिग्रहण का काम जारी रखा.

ग्रामीणों के विरोध से भी एजेंसियों के कानों पर जूं नहीं रेंगी क्योंकि वे भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 17 के तहत आपातकालिक प्रावधान का इस्तेमाल करती रहीं. इस प्रावधान के तहत वे अधिग्रहण अधिसूचना प्रकाशित होने के 15 दिन बाद किसी जमीन पर कब्जा कर सकती हैं. आवास एजेंसियों ने इस मामले में अदालती आदेशों को भी ताक पर धर दिया.

इन एजेंसियों को अब ग्रामीणों का गुस्सा ही सही रास्ते पर ला सकता है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत की अगुआई में चल रहे आंदोलन की एक मांग भी यही है कि किसानों को उनकी जमीन का पर्याप्त मुआवजा दिया जाए.

कई गांवों में तो किसानों ने जवाबी कार्रवाई भी की है. 11 फरवरी को हरदोई मार्ग पर, राजधानी से कोई दस किलोमीटर दूर बड़ी कलां गांव में लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की आवास कॉलोनी के लिए नींव खोदी जा रही थी, तभी गांववालों और ठेकेदारों, मजदूरों में संघर्ष हो गया. गोली बारी हुई. हजारों गांववालों ने रास्ता जाम कर दिया. वे तभी वापस गए जब स्थानीय प्रशासन ने वायदा किया कि एलडीए मुआवजे का मसला निबटाने के बाद ही काम शुरू करेगा. बड़ी कलां के आसपास और पड़ोस के तीन गांवों में एलडीए ने 750 एकड़ जमीन अधिग्रहित की है. इसमें ज्यादातर खेती की जमीन है. गांववालों को पिछले साल पांच से नौ पैसे प्रति वर्ग फुट मुआवजा देने का प्रस्ताव था जबकि उस जगह की स्टांप शुल्क दर 15 से 25 रुपए वर्ग फुट है.

मेरठ के आसपास के गांवों की भी यही

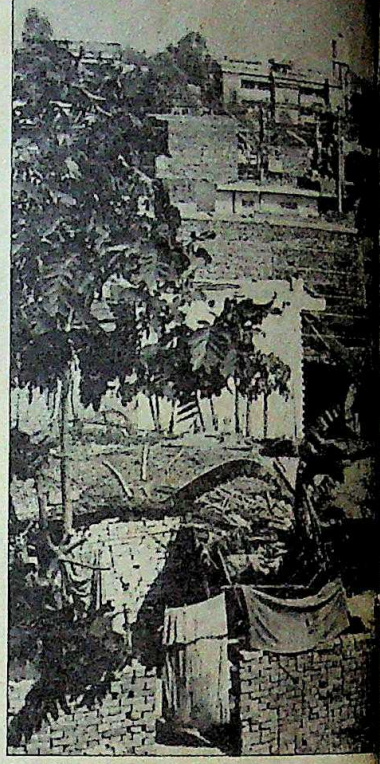

सभी फोटो: आर.के. गुप्ता

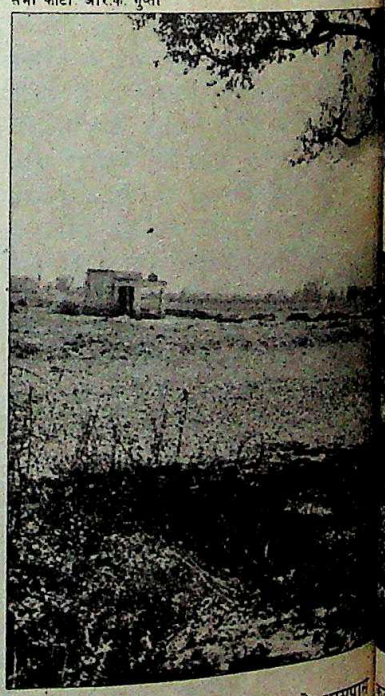

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

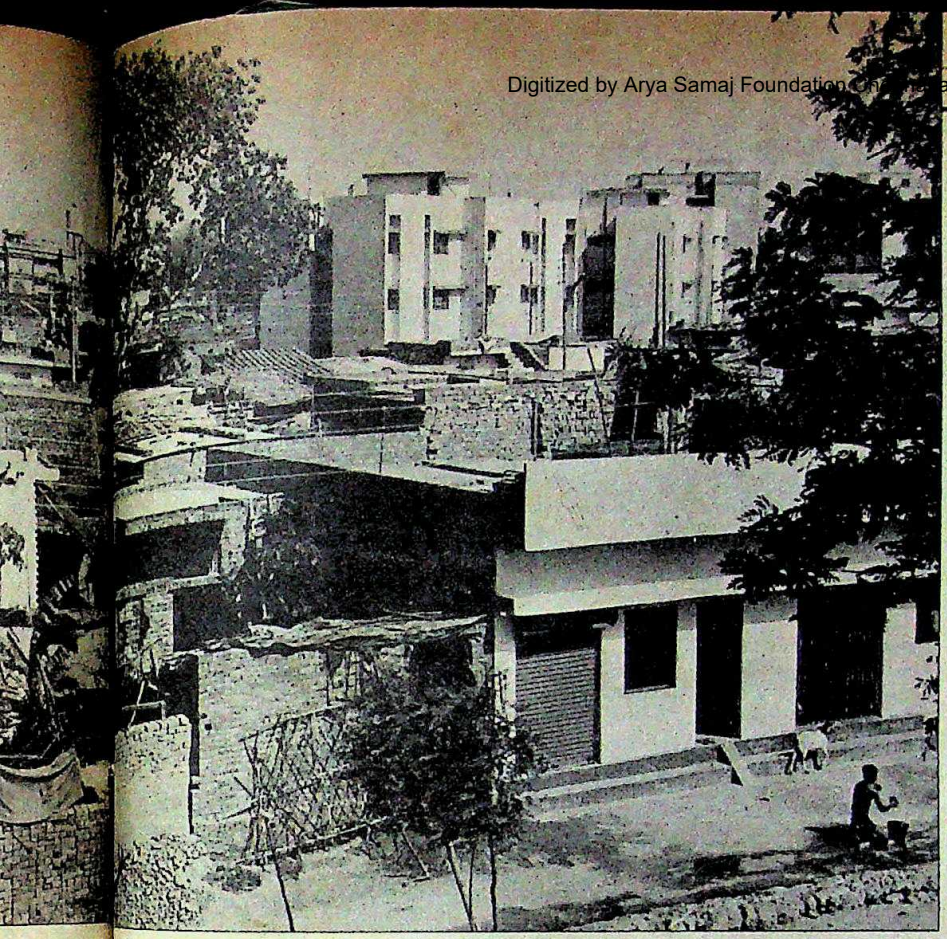

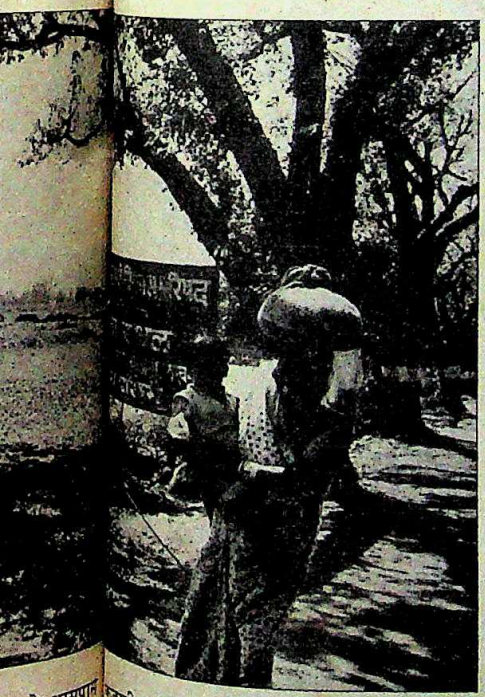

लखनऊ के एक गांव में घुसपैठ करती एक शहरी कॉलोनी; और (बाएं) मुआवजे के झगड़े वाली जमीन: पुराना मसला

कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) का भी यही रोना है. प्राधिकरण तो कानपुर नगर महापालिका द्वारा पहले अधिग्रहित की गई जमीन तक का कब्जा नहीं ले पाया है. बरसों पहले अधिग्रहित इस जमीन पर खेती कर रहे किसान अब अनुग्रह राशि की मांग कर रहे हैं. मांग मान ली गई तो प्राधिकरण पर 100 करोड़ का बोझ बढ़ेगा.

गांववालों का गुस्सा इसलिए भी भड़का क्योंकि उन्हें लगता है कि ये एजेंसियां उनसे गुठलियों के दाम जमीन खरीदती हैं और फिर उसे ऊंची कीमत पर बेचकर भारी मुनाफा कमा रही हैं. ये एजेंसियां चार पैसे प्रति वर्गफुट से लेकर दो रुपए प्रति वर्गफुट तक मुआवजा देती हैं. उस पर 5 से सात रुपए प्रति वर्गफुट के हिसाब से विकास के लिए खर्च करने के बाद 25 से 40 रुपए प्रति वर्गफुट की दर से बेच देती है.

अब एलडीए का ही उदाहरण लीजिए. इसने लखनऊ में अलीगंज और गोमती नगर आवास योजनाओं के लिए 70 पैसे से 1.75 रु. प्रति वर्गफुट की दर पर जमीन हासिल की, जबकि यहां जमीन की स्टांप शुल्क दर 12 से 22 रुपए प्रति वर्गफुट के बीच थी. एलडीए ने गृह निर्माण के लिए 30 से 35 रुपए प्रति वर्गफुट की दर से जमीन बेची, जबकि व्यावसायिक उद्देश्य के लिए बेची गई इस जमीन की कीमत रखी गई 250 से 450 रुपए प्रति वर्गफुट.

इन बढ़े-चढ़े दामों पर जमीन बेचने के बावजूद ज्यादातर एजेंसियां कंगाली की हालत में हैं. एलडीए के उपाध्यक्ष शैलेष कृष्ण दत्त बदहाली की सफाई देते हैं, "आर्थिक रूप से पिछड़े तबकों के लिए जमीन और मकान उपलब्ध कराने की वजह से हमने भारी नुकसान उठाया है." पर यह आधा सच है. ज्यादातर एजेंसियों ने तो यह काम सिर्फ कागजों पर ही किया है. उदाहरण के लिए एलडीए 40 फीसदी घर गरीबों को देने की बात करती है पर आंकड़े इसे 10 फीसदी के आसपास ही ठहराते हैं. एजेंसियों की तंगहाली के कारण किसानों को किया जाने वाला भुगतान या तो लटका रहता है या फिर रकम घटा दी जाती है. उत्तर प्रदेश के शहरी विकास सचिव एस.डी. बागला राजस्व विभाग के ताजा आदेश के खिलाफ इसी तरह की दलीलें देते हैं. वे कहते हैं कि एजेंसियां जमीन तभी 32 रुपए प्रति वर्गफुट की दर से बेच सकती हैं जब वे किसानों को 1.50 रुपए प्रति वर्गफुट की दर से मुआवजा दें. इसकी वजह यह है कि अधिग्रहित जमीन का सिर्फ 55 फीसदी हिस्सा ही गृह निर्माण के लिए बेचा जा सकता है, बाकी जमीन सड़कों, अस्पताल, स्कूल व पार्क वगैरह के लिए छोड़नी पड़ती है. तिस पर विकास का खर्च भी बैठता है और उधार रकम पर ब्याज भी. बागला कहते हैं कि अगर आवास व स्थानीय विकास संगठनों को अधिग्रहित जमीन का 20 रुपए प्रति वर्गफुट मुआवजा देने को कहा गया तो वे 73 रु. प्रति वर्गफुट से कम पर जमीन नहीं बेच सकेंगे.

राजस्व विभाग के सचिव संतकुमार त्रिपाठी अपने रवैये पर अडिग हैं. वे कहते हैं, "सरकार का यह आदेश मंत्रिमंडल के उस फैसले के बाद जारी हुआ जो मंत्रिमंडल ने किसानों के हितों का ख्याल रखते हुए किया था." हालांकि त्रिपाठी यह भी कहते हैं कि उनका विभाग बागला की बात पर 'कानूनी नजरिये से' विचार कर रहा है.

समस्या यह है कि मंत्रिमंडल आवास एजेंसियों पर ज्यादा मुआवजे के लिए दबाव नहीं डाल सकता. मामला चूंकि किसानों के हित, शहरियों की समस्या और नाकारा सरकारी एजेंसियों के बीच उलझा है इसलिए राजनैतिक अलंबरदार हालत को जस का तस ही बना रहने देंगे. किसानों की यही बदकिस्मती है.

—दिलीप अवस्थी

कहानी है. मेरठ विकास प्राधिकरण (एमडीए) ने पिछले साल यहां 5,200 एकड़ जमीन अधिग्रहित की थी पर आज तक उस पर कब्जा हासिल नहीं कर सका. किसानों का एक संगठन भूमि प्रतिरक्षा समिति वहां जोरदार प्रतिरोध कर रहा है, इससे प्राधिकरण की और 22,000 एकड़ जमीन शामिल करने की योजना टल गई है.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

क्या आप सोचते हैं कि दूसरे सूटकेस बनानेवाले सिर्फ़ दाम ही गिराते हैं...?

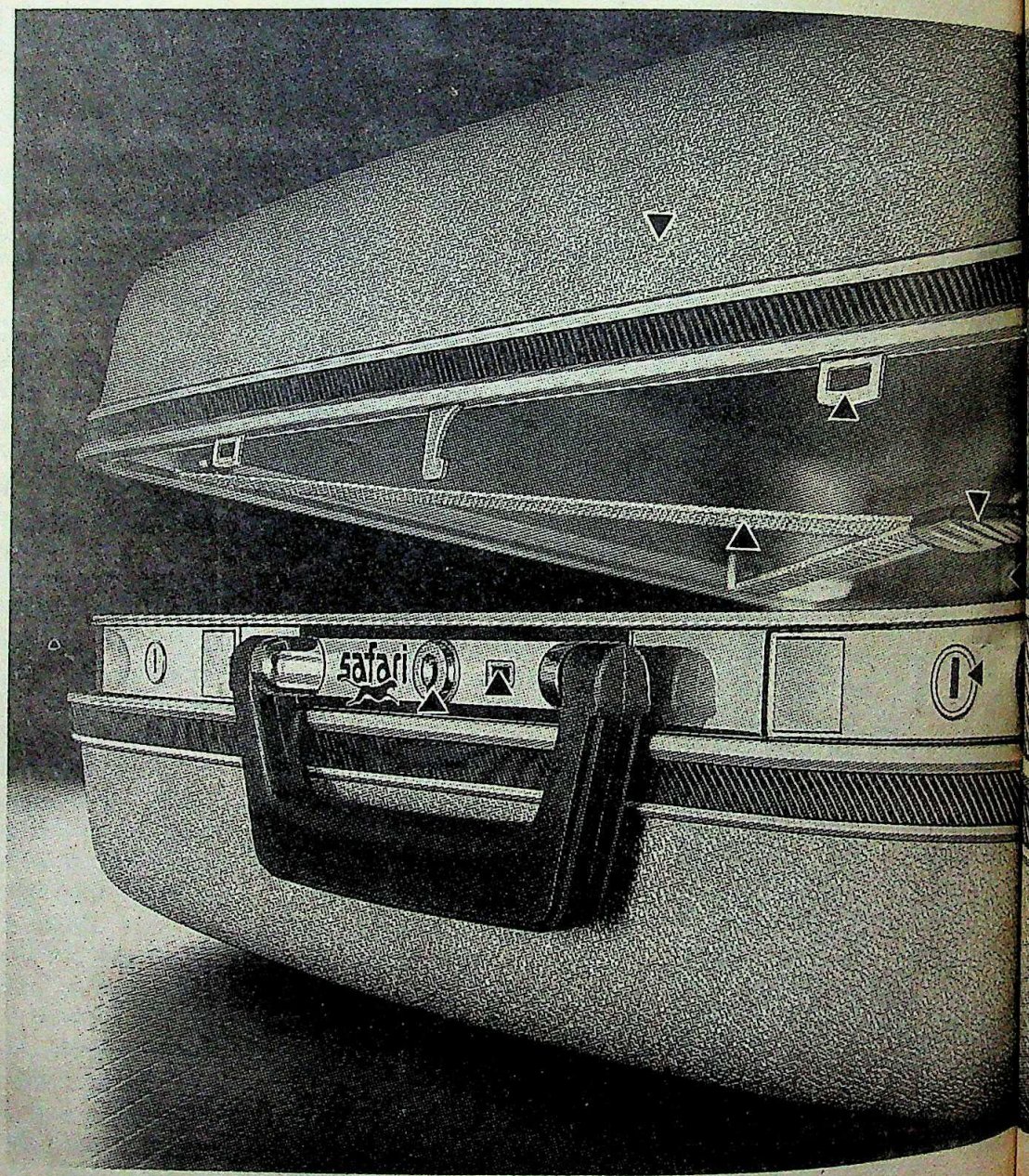

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

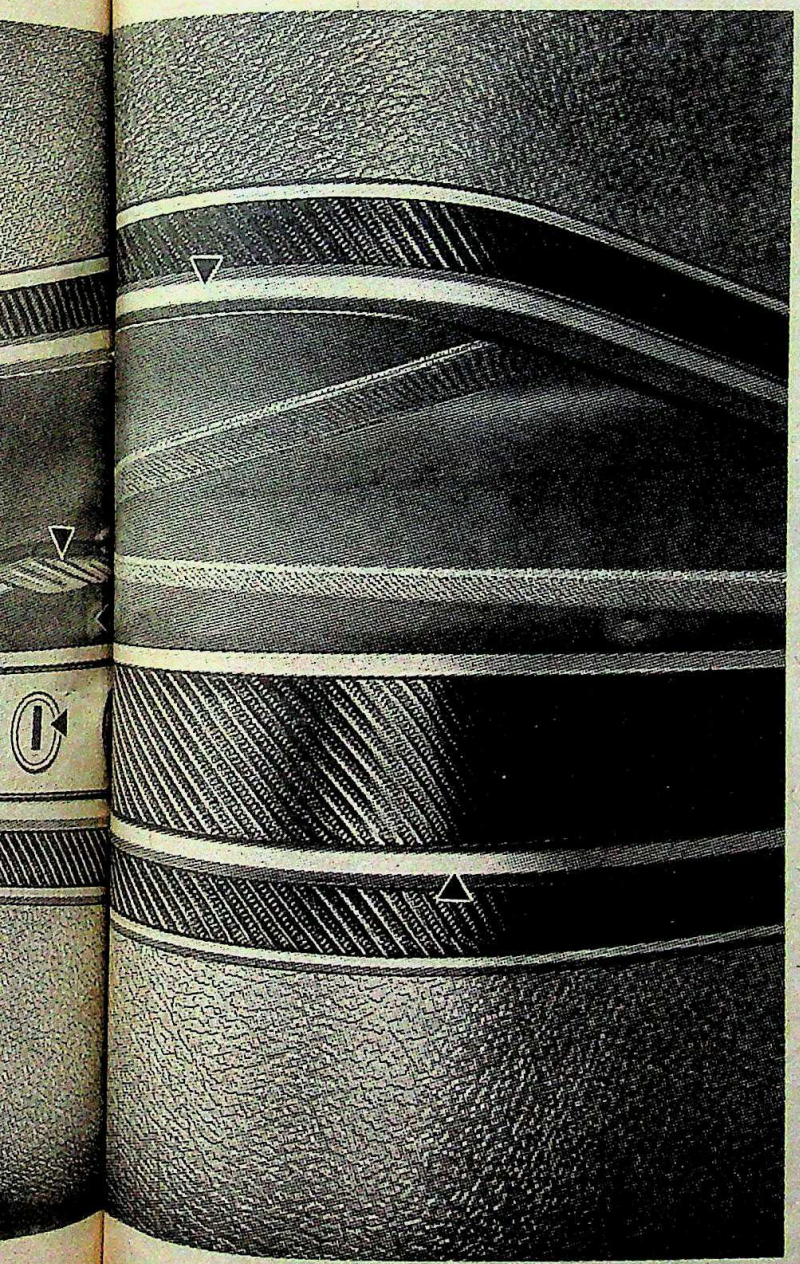

लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती.

बेशक सफ़ारी से सस्ते सूटकेस खरीद सकते हैं आप.
लेकिन कम कीमत में आपको मिलती है सस्ती क्वालिटी.

सफ़ारी के ख़ास डिज़ाइन वाले ज़्यादा मज़बूत फ्रेमों की जगह दूसरे सूटकेसों में आपको मिलेंगे अल्यूमीनियम के मामूली फ्रेम.

या सफ़ारी के ज़्यादा दिन चलनेवाले क्रोमियम-प्लेटेड कब्ज़ों की

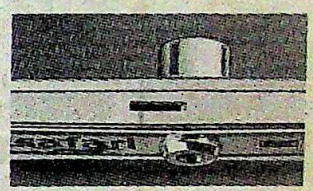

जगह मिलेंगे मामूली ज़िंक-प्लेटेड कब्ज़े. या सफ़ारी के ६ लीवर वाले मशहूर वॉल्ट लॉक की जगह लगे होंगे ५ लीवर के साधारण ताले.

या फिर शायद ताले हों ही नहीं. औरों के सूटकेसों में प्लास्टिक शेल पर रिवेट सीधे ही लगा दिये जाते हैं जिससे उनका शेल कमज़ोर पड़ जाता है. लेकिन सफ़ारी में, जैसे कि, 'गैलेक्सी 2001'

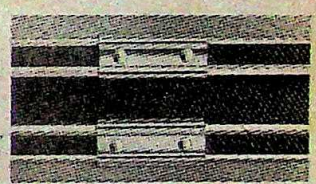

सूटकेसों में दोनों ओर धातु पर ही रिवेट लगाये जाते हैं.

और हां, उनमें आपको नहीं मिलेंगी टॉयलेट पाउच, ज़िप पॉकेट वाले डिवाइडर और अनोखे बकल-डाउन-सिस्टम जैसी सुविधाएं जो कि हमारे 'गैलेक्सी 2001' में मिलती हैं.

और न ही आपको मिलेगी ऊंची क्वालिटी क़ायम रखने के लिए की जाने वाली वैसी कड़ी जांच जैसी कि हम हर सफ़ारी की ९० अलग-अलग बातों के लिए करते हैं.

देखा आपने, तभी तो सफ़ारी दे पाता है आपके पैसे की सही-सही कीमत.

और तभी तो हम किसी भी कीमत पर क्वालिटी बिगड़ने नहीं देते.

safari

भरी हैं इसमें सैकड़ों खूबियां.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दूरदर्शन

बड़ी योजनाओं के छोटे नतीजे

न अच्छे कार्यक्रम, न अच्छी फिल्में और न कोई सुविचारित नीति

जैसे सोते में कोई अचानक उठकर पी.टी. उषा की तरह दौड़ने लगे और फिर धड़ाम से गिर पड़े. उत्साह से शुरू किए गए कई महत्वकांक्षी कार्यक्रमों के हश्र से तो कम-से-कम यही जाहिर होता है.

अमेरिका, ब्रिटेन और रूस की प्रसारण अवधि का मुकाबला करने के लिए पिछले साल 23 फरवरी को सुबही दूरदर्शन शुरू किया गया. जिन उद्देश्यों को लेकर यह प्रसारण शुरू किया गया था वह इसमें कहीं नजर नहीं आता. पूर्व सूचना प्रसारणमंत्री विट्ठल गाडगिल, जिनके कार्यकाल में इस प्रसारण की योजना बनी थी, का कहना है "मार्निंग टीवी शुरू करने का हमारा 'कंसेप्ट' था समाचार और एक बहुत ही हल्का ऐसा आइटम जो सुबह-सुबह अच्छा-सा मूड बना सके. अब यदि वह बात नहीं है तो मैं यही समझूंगा कि मेरा 'कंसेप्ट' ही गलत था."

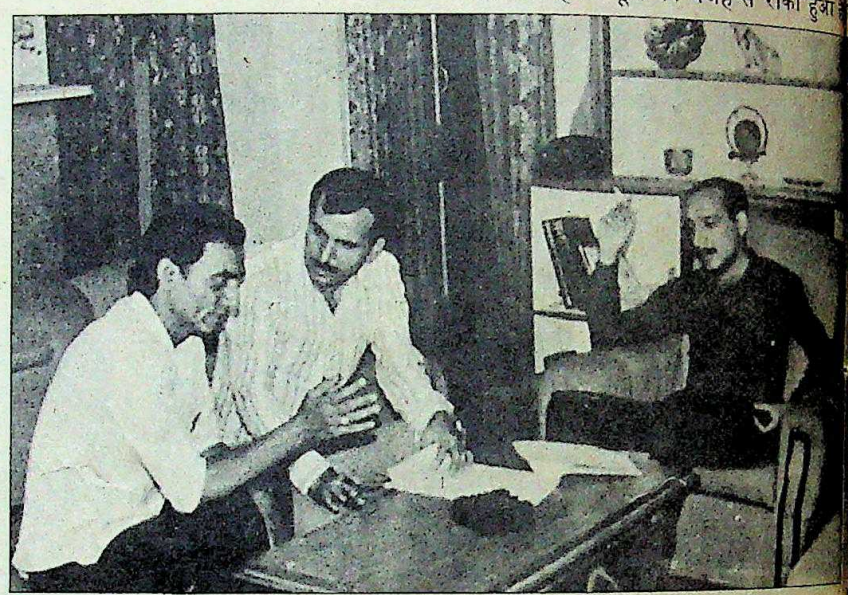

'कुंवर साहब': ढाई कोस का सफर

"सुबह खबरों के साथ हल्का आइटम देने का विचार था. ऐसा नहीं हो रहा यानी हमारी धारणा ग़लत थी"

बी.एन. गाडगिल
पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री

दूरदर्शन के पूर्व महानिदेशक हरीश खन्ना की भी यही राय है, "मार्निंग ब्रॉडकास्ट बनाया तो मैंने ही था. पर मुझे स्वीकार करने में शर्मिंदगी नहीं है कि बात बनी नहीं. प्रधानमंत्री, गाडगिल और हम चाहते थे कि रात 12 बजे के बाद जो घटनाएं हुई उसे सुबह-सुबह दिखाया जा सके. लोग रात को सो जाएं पर हमारा 'न्यूज यूनिट' रात भर जागकर काम करे. इसके अलावा जो घटना रात 9 बजे दिखाई जा चुकी है उसमें से खास-खास का विश्लेषण सुबह दिखाया जाए."

पर दूरदर्शन के महानिदेशक भास्कर घोष कुछ और ही बात कहते हैं, "मुझे नहीं मालूम कि 'ओरिजिनल आइडिया' किसका था. लेकिन हेल्थ, न्यूज, कॉमेडी कवर करने की बात थी और वह हो रही है. सर्वे बताता है कि इस प्रसारण के दर्शक लाखों में नहीं, करोड़ों में हैं."

लोग 21वीं सदी में पहुंचने के योग्य हो सकें शायद इसलिए 7 अप्रैल '87 को दूरदर्शन पर देर रात की फिल्मों की शुरुआत हुई. यहां भी वयस्क फिल्म 'अर्थ' से इसकी शुरुआत हुई. सप्ताह में दो दिन मंगल और शुक्र की रात को इन फिल्मों का दिखाया जाना तय हुआ लेकिन दो महीने के भीतर दूरदर्शन तंत्र जवाब दे गया और 23 जून से मंगल की फिल्में आनी बंद हो गई.

शुक्र की रात की फिल्मों का सिलसिला जैसे-तैसे 28 अगस्त तक क्यूबा की फिल्म 'सिसीलिया' तक चला. पर ग्रहण के कारण उपग्रह सेवा नहीं मिल सकी. और देर रात की फिल्मों का प्रसारण लगभग दो महीने तक रोक दिया गया. अब मई के आखिरी शुक्रवार से यह सिलसिला फिर शुरू करने की घोषणा की गई है. भारतीय तथा विदेशी फिल्में वैकल्पिक क्रम में दिखाने की योजना है. देर रात दिखाई जाने वाली हिंदी फिल्मों में 'चेतना', 'मंडी', 'कथा' और 'एक बार फिर' जैसी फिल्में गिनाई गई हैं पर योजना के मूर्तरूप लेने पर ही असलियत पता लगेगी.

देर रात की फिल्मों के प्रसारण न होने के बारे में दूरदर्शन के उपमहानिदेशक अलबेल सिंह गरेवाल कहते हैं, "इन फिल्मों का प्रसारण हमने सूखे की वजह से रोका हुआ है क्योंकि पैसों की कमी रही है." पर सच तो यह है कि देर रात को दिखाए जाने लायक अच्छी फिल्में दूरदर्शन के पास हैं ही नहीं.

अच्छी फिल्मों की कमी की बात शनिवार शाम को प्रसारित विभिन्न भारतीय भाषाओं की फिल्मों से भी स्पष्ट होती है. इन फिल्मों की शुरुआत हालांकि एक अच्छी कोशिश रही क्योंकि हिंदी फिल्मों के अलावा हरियाणवी, पंजाबी, भोजपुरी, सिंधी, गढ़वाली वगैरह में बनने वाली फिल्में भी लोग देख सकते हैं. पर यह प्रसारण नियमित नहीं हो पा रहा है. इस अवधि में जो फिल्में दिखाई गई उनमें कुछ को छोड़कर अधिकतर का स्तर बहुत घटिया रहा. पंजाबी फिल्म 'माता दा दरबार' 'गुलाबो' और 'दंगल' जैसे नाम इस बात के साक्षी हैं. और 9 अप्रैल को 'संपूर्ण रामायण' दिखाने का क्या मकसद हो सकता था रामनवमी या विजय दशमी भी नहीं थी. इन दिनों 'रामायण' सीरियल भी चल रहा है.

दरअसल इन फिल्मों के प्रसारण में दूरदर्शन का एक उद्देश्य यह भी था कि वह ऐसी फिल्मों को इस प्रसारण में दिखा सकेगा जो लंबे अरसे से उसके पास स्वीकृत पड़ी हैं. स्वीकृत फिल्में वे थीं जो उसने 1983 और '85 के दौरान गुरुवार के प्रसारण के लिए

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'जान आफत में': फूहड़ हास्य

दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक शिव शर्मा कहते हैं, "लगभग 5100 लोगों ने इस पंजीकरण के लिए आवेदन किया था. हमने आवेदनपत्रों की छंटाई कर ली है और बैठकें चल रही हैं, कमेटी भी बन गई है. आखिरकार पांच हजार आवेदनों की जांच में कुछ समय तो लगेगा ही."

दूरदर्शन की एक और योजना संवाददाताओं तथा समाचार संपादक वगैरह की नियुक्ति की तो अब पूरी तरह लटकी हुई लगती है. इन नियुक्तियों के लिए अखबारों में तो कई बार बड़े विज्ञापन दिए ही गए साथ ही दूरदर्शन ने अपने राष्ट्रीय प्रसारण में भी कई दिन इन नियुक्तियों के आवेदन की घोषणा की. बाद में इसके लिए लिखित परीक्षा हुई और साक्षात्कार भी. इस सब पर लाखों रुपए पानी की तरह खर्च किए गए. पर 'इंडियन इन्फर्मेशन सर्विस' के लोगों ने केंद्रीय न्याय प्राधिकरण में याचिका दायर कर दी कि दूरदर्शन इस तरह बाहर से नियुक्तियां नहीं कर सकता और उन्हें स्थगनादेश मिल गया. उम्मीदवारों का कहना है कि दूरदर्शन चाहे तो इस मामले का फैसला बहुत जल्द हो सकता है. हालांकि घोष कहते हैं, "हर चीज में कुछ न कुछ वक्त तो लगता ही है. यह नहीं कि सब फटाफट हो गया. हम तो खुद इसे जल्दी निबटाना चाहते हैं."

पर दूरदर्शन की 'जल्दी' का क्या अर्थ है इसकी मिसाल दिल्ली दूरदर्शन का धारावाहिक 'कुंवर साहब' भी देता है. पिछले साल के शुरू में दिल्ली दूरदर्शन ने लेखक चिरंजीत के इस धारावाहिक का निर्माण शुरू किया था. इसके निर्देशन के लिए दूरदर्शन ने बंबई फिल्म और रंगमंच के अभिनेता टी.पी. जैन को दिल्ली बुलाया. बड़े जोर-शोर से नई दिल्ली की महादेव रोड स्थित कोठी नं. 27 में इसकी शूटिंग शुरू की गई. बहुत तेजी से इसके 6 एपिसोड पूरे भी हो गए. इन 6 एपिसोड को पूरे हुए छह महीने से भी अधिक हो गए हैं पर सीरियल अभी वहीं अटका हुआ है जहां छह महीने पहले था.

दिल्ली दूरदर्शन केंद्र की निदेशक जयचंदी राम ने पहले कहा था कि कुंवर साहब का कुछ काम बाकी है, शायद इसे मार्च-अप्रैल तक शुरू करें. अब वे कहती हैं, "हां, इसे शुरू करने में अभी भी कुछ दिक्कतें हैं. शायद मई में इसे शुरू कर पाएंगे."

पर सीरियल से जुड़े लोगों का कहना कुछ और ही है. एक सूत्र ने बताया कि केंद्र निर्देशक इस सीरियल से नाखुश हैं. दरअसल निर्देशक ऐसी-ऐसी सुविधाएं मांग रहे हैं जो दूरदर्शन को न्यायसंगत नहीं लगतीं. जैसे वे मंदिर की एक शूटिंग के लिए वृंदावन जाना चाहते हैं जबकि दूरदर्शन अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली में इतने मंदिर हैं तो वृंदावन जाने की क्या जरूरत है? जैन कहते हैं, "राधा कृष्ण का जैसा मंदिर हमें चाहिए वह वृंदावन में है, दिल्ली में नहीं. वैसे सीरियल का काम एडिटिंग की वजह से रुका हुआ है,

'कुंवर साहब' की ऐसी कैसी एडिटिंग है जो पिछले छह महीने से नहीं हो पा रही यह सोचा ही जा सकता है. लगता है इस सीरियल में किसी की दिलचस्पी नहीं है. चाहे उस पर दूरदर्शन का कितना ही पैसा लग चुका है. इस बीच 'कुंवर साहब' को अधर में छोड़कर दिल्ली दूरदर्शन ने एक और सीरियल 'फिर उसी वीराने की तलाश' शुरू कर दिया है. यानी रफ्तार वही बेढंगी रहेगी.

—प्रदीप सरदाना

"खबरों के साथ स्वास्थ्य, कॉमेडी कवर कियां जा रहा है. सुबह के दर्शक लाखों नहीं करोड़ों हैं"

भास्कर घोष
महानिदेशक, दूरदर्शन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कर्नाटक

बड़ी कामयाबी

सबसे ज्यादा सोना बरामद

लोगों के मन में प्रवर्तन अधिकारियों की कोई अच्छी छवि नहीं है. वे उन्हें सुस्त किस्म के ऐसे घपलेबाज मानते हैं जो मौका-ए-वारदात पर तभी पहुंचते हैं जब सब कुछ हो चुका होता है. पर पिछले महीने कर्नाटक में मंगलूर से 96 किलोमीटर दूर उत्तर में गंगोल्ली नामक स्थान पर 10.5 करोड़ रु. कीमत का सोना पकड़े जाने से तस्वीर का रुख ही बदल गया.

देश में अब तक पकड़ी गई इस सबसे बड़ी खेप में सोने के 2,740 बिस्कुट बरामद हुए जिनका वजन करीब 3.2 क्विंटल है. मार्के की बात यह रही कि यह सोना बहुत ही शुद्ध है और दुनिया की दो आला कंपनियों से आया था. इसमें 80 फीसदी पर स्विट्जरलैंड की क्रेडिट सुइस का और बाकी पर लंदन की जॉनसन ऐंड मैथे का ठप्पा लगा हुआ है.

इस कार्रवाई की अहमियत कुछ और वजहों से भी है. इस अभियान के सूत्रधार सीमा शुल्क विभाग के अतिरिक्त कलेक्टर आर.जे. मनोहर बताते हैं, "भारत में यह पहला मौका है जब सोना उतारते ही पकड़ लिया गया." अमूमन सोने का पता उस समय चलता है जब वह कहीं बीच रास्ते में ही हो, किसी गाड़ी में या घर में. इस तरह तस्करी करके लाए गए सोने का कुछ हिस्सा ही बरामद हो पाता है.

7 अप्रैल को हुई इस कार्रवाई के लिए बड़ी मुस्तैदी से पांच महीने तक योजना बनाई जाती रही. पिछले नवंबर में सीमा शुल्क विभाग को एक मुखबिर ने सूचना दी थी कि दिल्ली और बंबई में सक्रिय तस्करों के एक गिरोह ने भारत-पाक सीमा पर निगरानी बढ़ जाने से अपना धंधा अब कोंकण तट पर स्थानांतरित कर लिया है.

उसी महीने जब कुछ बाहरी लोग और उनकी गाड़ियां गंगोल्ली के पास देखी गईं तो यह बात सही लगने लगी. पर ज्यों ही अधिकारियों ने अभियान की योजना बनाई उन्हें लगा कि इस मामले में पूर्ण गोपनीयता बरतना बेहद जरूरी है, इसीलिए विभाग के इंस्पेक्टर अलग-अलग वेश में फर्जी नंबर प्लेट लगी कई गाड़ियों में वहां घूमते थे. कुछ तो स्थानीय मछुआरों की तरह रंगदार लुंगी पहने इठलाते हुए वहां टहला करते.

मेहनत रंग लाई और वे उस जगह का पता लगाने में कामयाब हो गए जहां सोना उतारा जाता था. यह गंगोल्ली के पास एक निर्जन जगह थी. उन्हें अंदेशा था कि यहां से 50 मीटर दूर टाइलों का छोटा सा घर गिरोह के ही किसी आदमी का है. अधिकारियों की खुशकिस्मती से वहां आस-पास कैसुएरिना के पेड़, झाड़ियां और चट्टानें थी जिनकी ओट में वे वहां पहुंच सकते थे.

फरवरी भर ये लोग इंतजार करते रहे. जब कुछ न हुआ तो वे निराश हो गए. पर अप्रैल शुरू होते ही उन्हें पता लगा कि तस्करी का माल दुबई से कुछ ही दिनों में पहुंच जाएगा. तब 12-12 सदस्यों की दो टीमें बनाई गईं—एक का नाम मोबाइल-एक और दूसरी का मोबाइल-दो रखा गया. हर एक को 48 घंटे की निगरानी का काम सौंपा गया.

अभियान में शरीक कस्टम वाले (दाएं); बरामद सोना

मोबाइल-एक ने 4 अप्रैल को पोजीशन ले ली पर उसका दो दिन का इंतजार बेकार गया. लेकिन राइफलों और रिवाल्वरों से लैस मोबाइल-दो ने जब पोजीशन ली तो उसी रात सोना उसके हाथ आ लगा. तड़के 4.45 बजे उन्हें दूर से आती हुई नौका की आवाज सुनाई दी जिसमें शक्तिशाली इंजन लगा था (मुख्य जहाज ने शायद कहीं दूर ही लंगर डाल दिए थे). नौका को मशीन-गन से लैस दो लोग खे रहे थे.

तभी चांदनी भरे तट पर न जाने कहां से आठ आदमी प्रकट हुए. चार मिनट में सारा काम खत्म हो गया. बोरों में लिपटे बारह बंडल उतार दिए गए.

वे आठों लोग ये बंडल उठाकर एक कतार में संकरे रास्ते पर उस घर की ओर बढ़ने लगे. वे घर के नजदीक पहुंचे ही थे कि कस्टम वालों की शक्तिशाली सर्चलाइट जल उठी. एक पल के लिए वे ठगे रह गए और फिर तेजी से भागकर घर के आंगन में घुस गए. लेकिन जब अफसरों ने कुछ गोलियां चलाईं तो उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया.

सोने को मूल पैकिंग में ही पकड़ लिया जाना सीमा शुल्क वालों के लिए बेहद खुशी की बात थी. उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इतना माल उनके हाथ लगेगा. टीम के एक सदस्य इंस्पेक्टर जोसेफ दियास कहते हैं, "जीवन में ऐसा सुनहरी मौका कभी-कभार ही हाथ लगता है."

इस अभियान में पकड़े गए लोगों में श्याम खन्ना के अलावा सभी व्यक्ति मोपला (केरल के मुस्लिम) मछुआरे हैं जिनमें तीन केरल के कासरगोड के और बाकी स्थानीय हैं. ये सभी लोग विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निरोधक कानून के तहत नजरबंद किए गए हैं.

मुखबिर और अधिकारियों दोनों को पुरस्कार दिए जाएंगे. मुखबिर को कर-मुक्त एक करोड़ रु. (हर 10 ग्राम सोने पर 350 रु.) मिलेंगे. मनोहर ने मुखबिर की जानकारी देने से इनकार कर दिया. उसकी पहचान खुल जाने का सीधा मतलब है मौत.

अभियान में शामिल 34 कस्टमवालों में एक करोड़ रुपए बराबर-बराबर बांटा जाएगा. हालांकि वरिष्ठ होने के नाते मनोहर को इसमें हिस्सा नहीं मिलेगा पर वे काफी संतुष्ट हैं. "जब मैंने देखा कि सोने के भार से मेज लगभग चरमरा रही है तो मुझे बहुत खुशी हुई." दरअसल विभाग की अच्छी छवि बहाल होना ही उनके लिए बड़ा पुरस्कार है.

—अवीक प्रताप

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

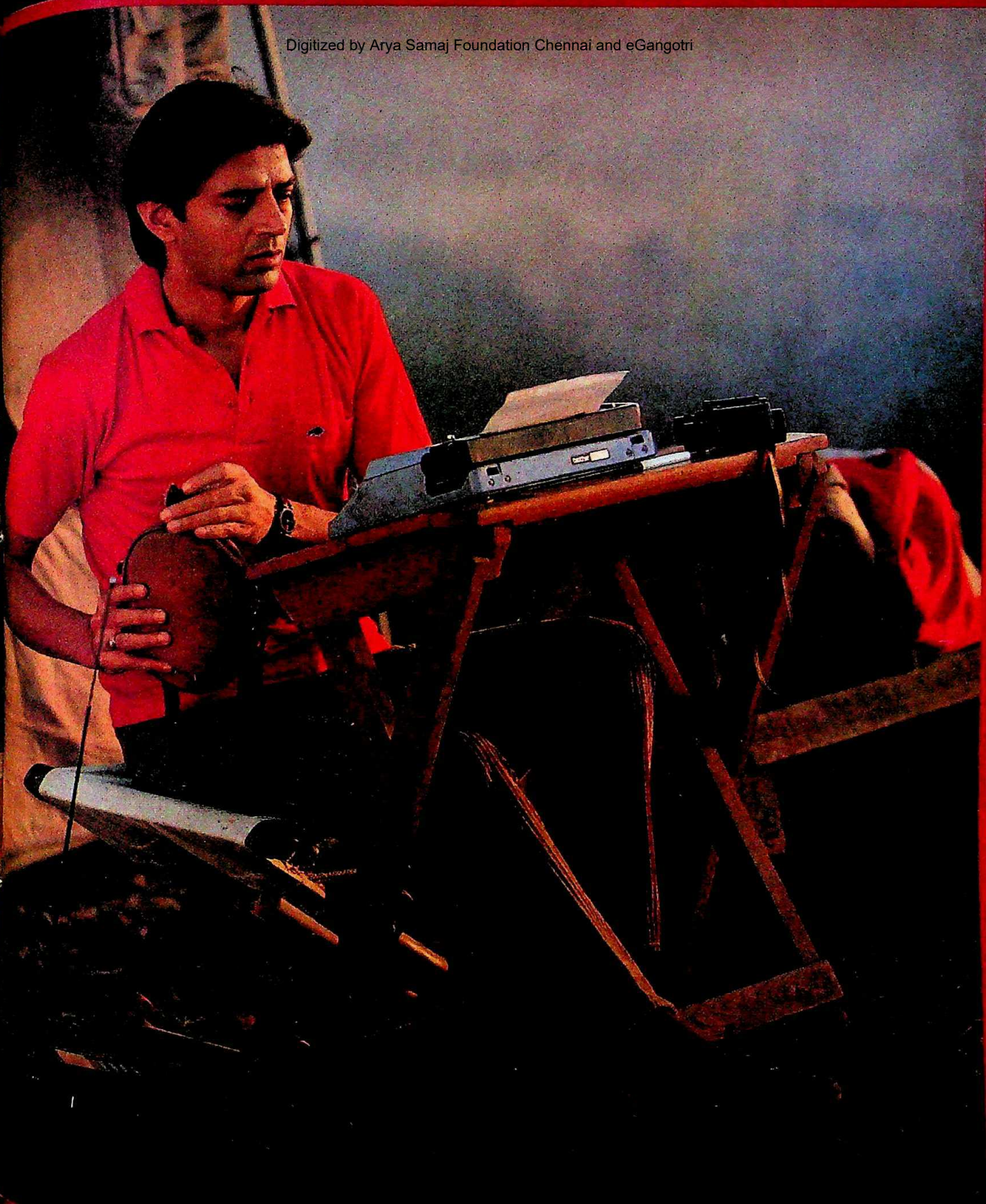

काफ़िलों में नहीं मिलते, जिनकी राहें जुदा होती हैं.

विदेशों में धूम मचाने के बाद अब बुल की भारत वापसी. यानी स्मैश अन्तर्राष्ट्रीय क्वालिटी के टी-शर्ट अब यहां भी उपलब्ध. शुद्ध, मुलायम कॉटन का शीतल आराम और आधुनिक फ़ैशन की शान का अनुपम मेल.

अपीगो मार्केटिंग प्रा. लि., मेकर चेम्बर्स III, [illegible] २३१८५५.

Smash International

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

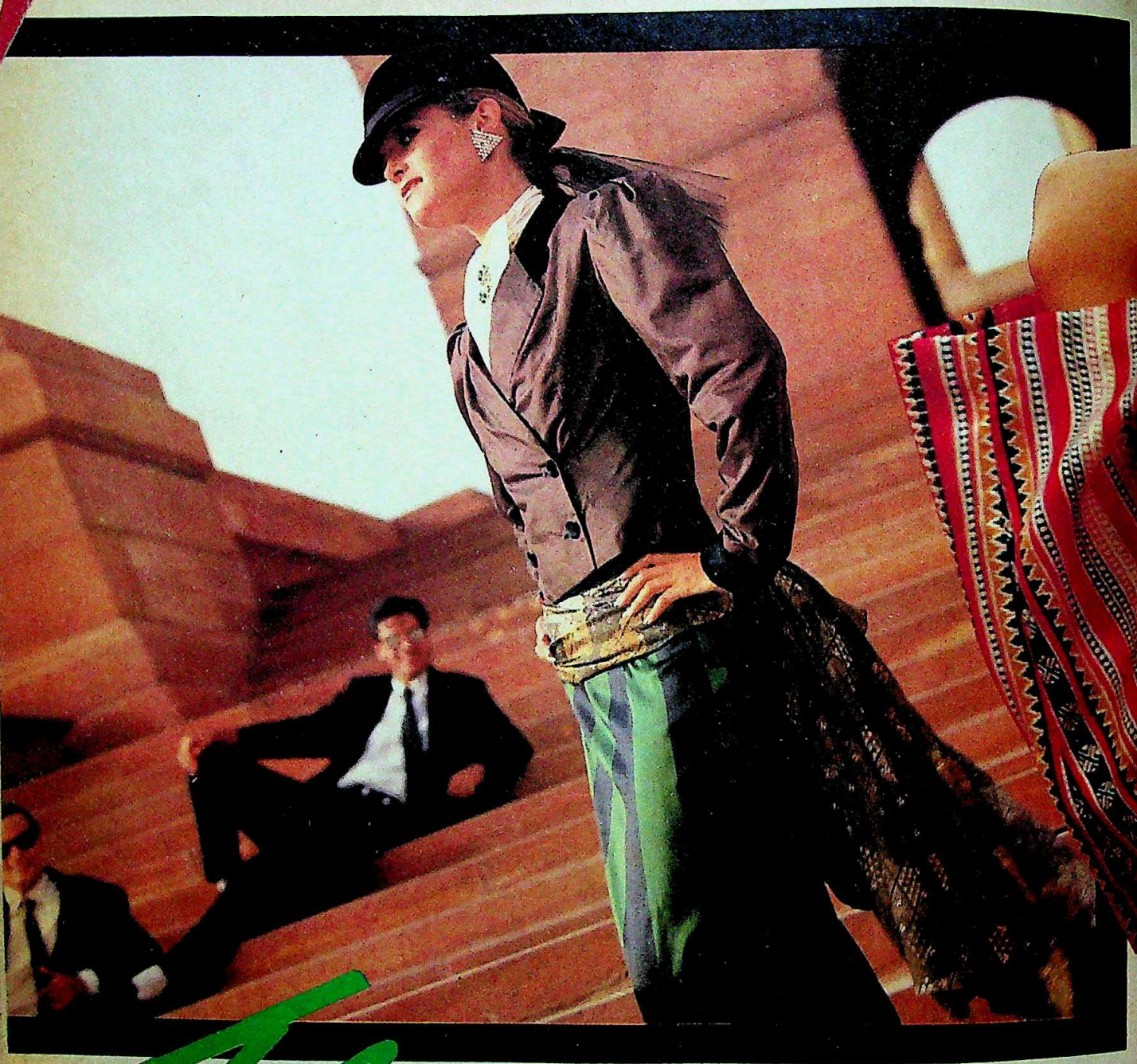

The Sun

VIMAL®
A RELIANCE PRODUCT

Dress Material

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Mudra.A.RIL. 4222

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

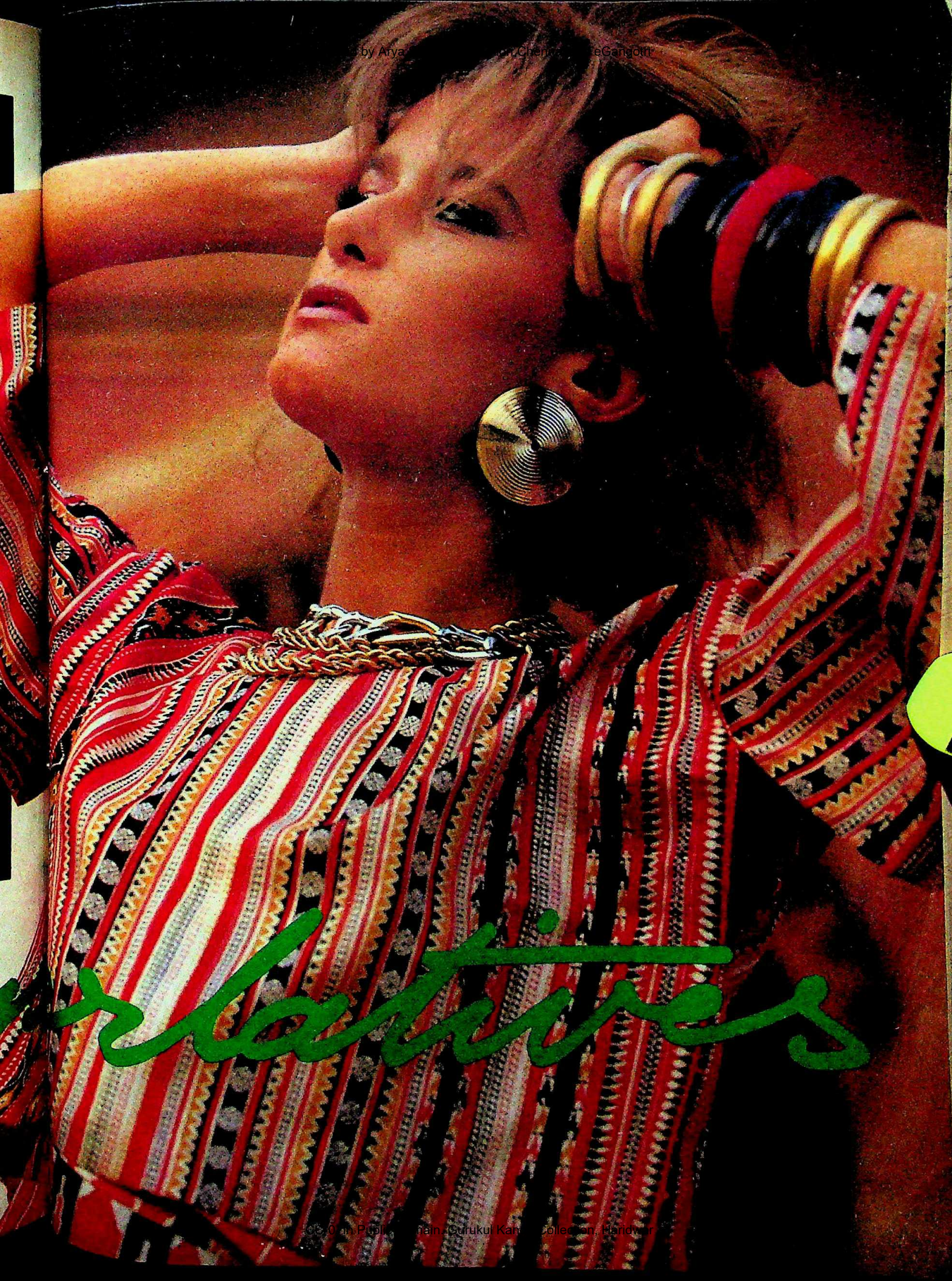

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गौतम राज्याध्यक्ष

• "हाइ! आई'म **अलीशा.** लोग प्यार से मुझे बेबीडॉल कहते हैं." हिंदी पॉप गायिका अलीशा चिनाय के बेबीडॉल कैसेटों के पहले गीत के इस मुखड़े ने खरीदारों को धड़ाधड़ आकर्षित किया है और पॉप गीतों की यह देसी मलिका 'कुच्ची कू', 'शोर शराबा', और 'ए फॉर एडल्टस ओनली' गीतों के जरिये लोगों की धड़कन बढ़ा रही है. लेकिन इन गीतों के मुखड़े उनकी धुनों से मेल नहीं खाते. अलीशा कहती है, "मेरे प्रशंसकों खासकर युवाओं में मेरी पहचान इन्हीं गीतों से है," अगर ऐसा है

अलीशा: गीतों की धड़कन

तो यह उसके लिए वरदान ही है. इन गीतों की धुनें उसके पति राजेश झावेरी उर्फ 'विज किंड' ने कंप्यूटर की मदद से तैयार की हैं. अलीशा अगस्त में इन कैसेटों का अंग्रेजी रूपांतरण जारी करेगी.

• आखिर उन्होंने घर बसा ही लिया. दो साल पहले 36 वर्षीय मुख्यमंत्री **प्रफुल्ल कुमार महंत** ने असम की जनता का दिल जीता था पर उनका अपना दिल अरसे से कैद में था. गुवाहाटी के कॉटन कॉलेज में जंतुविज्ञान की लेक्चरार **जयश्री गोस्वामी** छात्र आंदोलन के जमाने से ही कंधे-से-कंधा मिलाकर उनका साथ देती रही हैं. राजनीति की मुश्किलों में फंसे होने से महंत

महंत और जयश्री: सादगी

पद्मा पटार जयंत दत्त

अपना विवाह टालते रहे. पर पिछले महीने के आखिर में वे जयश्री के साथ परिणयसूत्र में बंध ही गए. महंत का कहना था, "मेरा खुश होना स्वाभाविक ही है." दूल्हे की मर्जी के मुताबिक यह 'सादा समारोह' ही रहा. नवदंपती ने केवल गुलदस्ते स्वीकार किए. कुछ हितैषी तोहफे लाए भी, पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें लौटा दिया. उन्होंने निमंत्रण पत्र पर लिखे संक्षिप्त नोट को शायद अनदेखा कर दिया था कि विवाह में कोई तोहफा न लाएं.

लाल और सुचित्रा: नया जीवन

राजन पोडवाल

• उधर मित्र लोग एक और नवदंपती को शुभकामनाएं देने जुटे थे. पिछले पखवाड़े मलयालम के लोकप्रिय अभिनेता 28 वर्षीय **मोहनलाल** भी तमिल फिल्म निर्माता के. बालाजी की बेटी **सुचित्रा** के साथ हमेशा के लिए बंध गए. दक्षिण के अमिताभ बच्चन माने जाने वाले मोहनलाल ने

श्याम टेकवानी

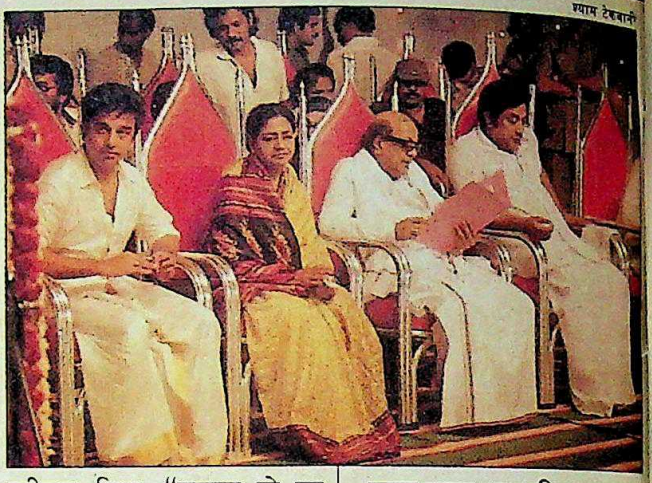

स्वीकार किया, "मामला तो यह प्रेम का था पर विवाह परंपरागत तरीके से ही हुआ." ज्योतिषी के शुभ लगन निकालने पर दंपती ने विवाह की रस्में अट्टुकल देवी के मंदिर में पूरी कीं. उसके बाद वे त्रिवेंद्रम क्लब पहुंचे जहां हजारों प्रशंसक पुलिस द्वारा आतंकित किए जाने के बावजूद उनकी राह ताक रहे थे. कई नेताओं समेत केरल के कई प्रबुद्ध लोगों के शामिल होने से यह यादगार विवाह बन गया. और तो और, मोहनलाल अपनी वास्तविक जिंदगी की फिल्म बनवाने में भी पैसे वसूलने से नहीं चूके. उनकी शादी की वीडियो फिल्म के सर्वाधिकार भारी रकम पर खरीदे गए हैं. इतने पैसे उन्होंने शायद शादी पर भी न लगाए हों.

• आपस में मारामारी कर रहे लोगों ने उस फिल्मी 'दादा' को हाथोहाथ ले लिया. 'नायकन' फिल्म में इंसाफ के लिए लड़ने वाले अपराधी की भूमिका निभाने के लिए **कमल हासन** को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला तो 9 मई को मद्रास में उनके अभिनंदन का कार्यक्रम रखा गया. इसमें द्रमुक के करुणानिधि, अन्नाद्रमुक की जानकी रामचंद्रन, इंका की कुमारी आनंदन और शिवाजी गणेशन समेत तमाम बड़े नेता शामिल हुए. कमल ने कहा, "मैं अपनी सिनेमाई छवि का इस्तेमाल सामाजिक मकसद के लिए कर रहा हूं."

कमल हासन: सामाजिक मकसद

उधर मंच पर विराजमान नेता दो लाख से ज्यादा की भीड़ का गद्गद होकर अभिवादन कर रहे थे. पर कमल या राज्य में बड़ी तादाद में मौजूद उनके प्रशंसक चुनावों में इन नेताओं में से किसका समर्थन करेंगे इस बारे में कमल अपने होंठ सिए ही रहे. वे कहते हैं, "मेरे प्रशंसकों का मानना है कि मुझे राजनीति से दूर ही रहना चाहिए."

• शब्दों को लेकर घमासान छिड़ने की संभावना है. साहित्य अकादमी ने 'भारतीय साहित्य का विश्वकोश' प्रकाशित किया तो उसमें लोकप्रिय बंगाली कवि **शक्ति चट्टोपाध्याय** का जिक्र भी था. कवि का जीवन परिचय देते हुए उसमें कहा गया है कि सेक्स में उनकी अत्यधिक सलिप्तता और नशीले पदार्थों की लत से उनकी कविता भी प्रभावित रही है. फिर क्या था, चट्टोपाध्याय का पारा सातवें आसमान पर जा पहुंचा. उनका कहना है, "मेरी जीवन शैली जो भी रही हो, मेरी कविता उससे अछूती ही रही. यह टिप्पणी दुर्भावनावश की गई है." मनुष्य और प्रकृति के प्रति दार्शनिक नजरिया रखने वाले और 63 किताबों के रचयिता शक्ति दा को 1983 में अकादमी के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. अब अकादमी पर मानहानि का मुकदमा ठोंकने वाले वे पहले लेखक हैं. उन्होंने पांच लाख रु. के नुकसान का दावा किया है उनके मुताबिक इससे उनकी किताबों की बिक्री घटी है.

शक्ति: मानहानि का मामला

के. चक्रवर्ती

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

121618
पुस्तकालय
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय
हरिद्वार

राजा की अग्निपरीक्षा

इलाहाबाद उपचुनाव जनमोर्चा नेता वी.पी. सिंह के लिए अगर करो या मरो का मामला बन गया है तो इंका के लिए भी इससे कम का नहीं. दूसरी ओर कांशीराम दोनों की संभावनाओं पर ग्रहण जैसे बन गए हैं. देश के सबसे संगीन उपचुनावों में से एक का आंखों देखा हाल.

आवरण कथा.....14

असंतोष की तीखी आंच

जनता पार्टी के असंतुष्टों ने आखिरकार पिछले पखवाड़े कर्नाटक के मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े को मात दे ही दी. विधान परिषद चुनावों में बागी उम्मीदवारों की जीत ने हेगड़े को वस्तुतः अल्पमत में और राज्य जनता पार्टी को टूट के कगार पर पहुंचा दिया.

आजकल.....26

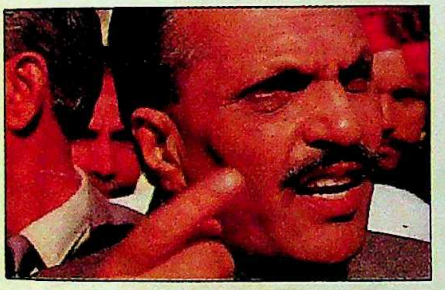

फिर अनिश्चितता का दौर

हर भविष्यवाणी को झूठा साबित कर देने वाले सदर जिया-उल-हक ने वजीरे आजम को बरखास्त करके पाकिस्तान में लोकतांत्रिक उम्मीदों पर पानी फेर दिया. उन्होंने नए चुनाव 90 दिन में कराने का वायदा किया. इस तख्तापलट और आगे की संभावनाओं का विश्लेषण.

खास रपट.....70

मिजाज का अंदाज लगाना मुश्किल

हाल के एक टीवी कार्यक्रम में इस साल अच्छे मानसून के बारे में की गई भविष्यवाणी ने विवाद पैदा कर दिया है. बहस का मूल मुद्दा है: क्या बारिश के बारे में लंबी अवधि की भविष्यवाणी की जा सकती है? मानसून के मिजाज का खास मुआयना.

खास रपट.....82

चप्पे-चप्पे पर चस्पां प्रचार

भीड़भाड़ भरा एक महानगर पूरी तरह विज्ञापनों से पट गया है. खरीदार की नजरे इनायत के लिए क्या-क्या नहीं किया जा रहा. नतीजा यह कि बंबई एक सार्वजनिक आर्ट गैलरी में तब्दील हो गई है. विज्ञापन की तकनीक और शैली के अनोखे नमूने पेश हैं वहां.

प्रचार माध्यम.....64

तस्करी की स्वर्णरेखा

भारत-नेपाल सीमा पर फैले खरीदारों के बाजार तस्करों के स्वर्ग ही हैं. इन दुकानों में परफ्यूम से लेकर वीसीआर तक हर चीज उपलब्ध है. राजधानी से महज कुछ घंटों की दूरी पर फलते-फूलते इस बाजार का तरतीबवार अंदरूनी ब्यौरा.

अपराध.....76

कसौटी.....9
तेवर.....10
राजरंग.....11
हिंदोस्तां हमारा.....12
बीता पखवाड़ा.....13
आवरण कथा
इलाहाबाद: राजा की अग्निपरीक्षा.....14
आजकल
कर्नाटक: असंतोष की तीखी आंच.....26
पंजाब: मौका खोने में माहिर.....28
मध्य प्रदेश: चौथे खंभे को जमीन.....30
कर्ज मेला: बिन मांगे मोती.....32
पश्चिम बंगाल: मुंशी पर मार.....32
ओडीसा: दामाद का दबदबा.....36
मिजोरम: सपना और संकट.....38
आखिरी बात.....44
राज्य-दर्पण.....45
विधि-विधान
किराया नियंत्रण विधेयक:
बड़े लोगों के फायदे में.....47
खास रपट
शंकरराव चव्हाण:
विदाई की अटकलें थमी नहीं.....48
विशेष लेख
दहेज हत्या:
दानवी जुनून का फैलता दायरा.....52
व्यापार-चक्र.....55
कारोबार
मजदूर संघ: विधेयक पर बवाल.....56
आयातित कारें: भरपूर भंडार.....61
शेयर बाजार: उत्साह बरकरार.....62
प्रचार माध्यम
विज्ञापन: चप्पे-चप्पे पर चस्पां प्रचार.....64
पास-पड़ोस
गुलबादीन हिकमतियार:
'चुनी हुई सरकार ही चाहिए'.....68
खास रपट
पाकिस्तान: फिर अनिश्चितता का दौर.....70
जगबीती
प्रधानमंत्री का विदेश दौरा:
सद्भावना की पूंजी के लिए.....74
अपराध
भारत-नेपाल सीमा:
तस्करी की स्वर्णरेखा.....76
रहन-सहन
ओडीसा: बीवी को बेचने की मजबूरी.....79
क्लिक.....80
खास रपट
मानसून: मिजाज का अंदाज लगाना मुश्किल..82
सिनेमा
राज कपूर:
नीली आंखों के सपने और सचाइयां.....86
टीवी
अमीर खुसरो: समन्वयवाद का सबक.....93
शिक्षा
कोचिंग केंद्र: धड़ल्ले से चलता धंधा.....94
परीक्षाएं: अंकों के लिए होड़.....96
धर्म
हिंदू मठ: समाधि से समाज सेवा तक.....97
किताबें.....99
चर्चित चेहरे.....104

आवरण: भवान सिंह

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

छवि जो दिल में उतर जाये... जे भी दी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

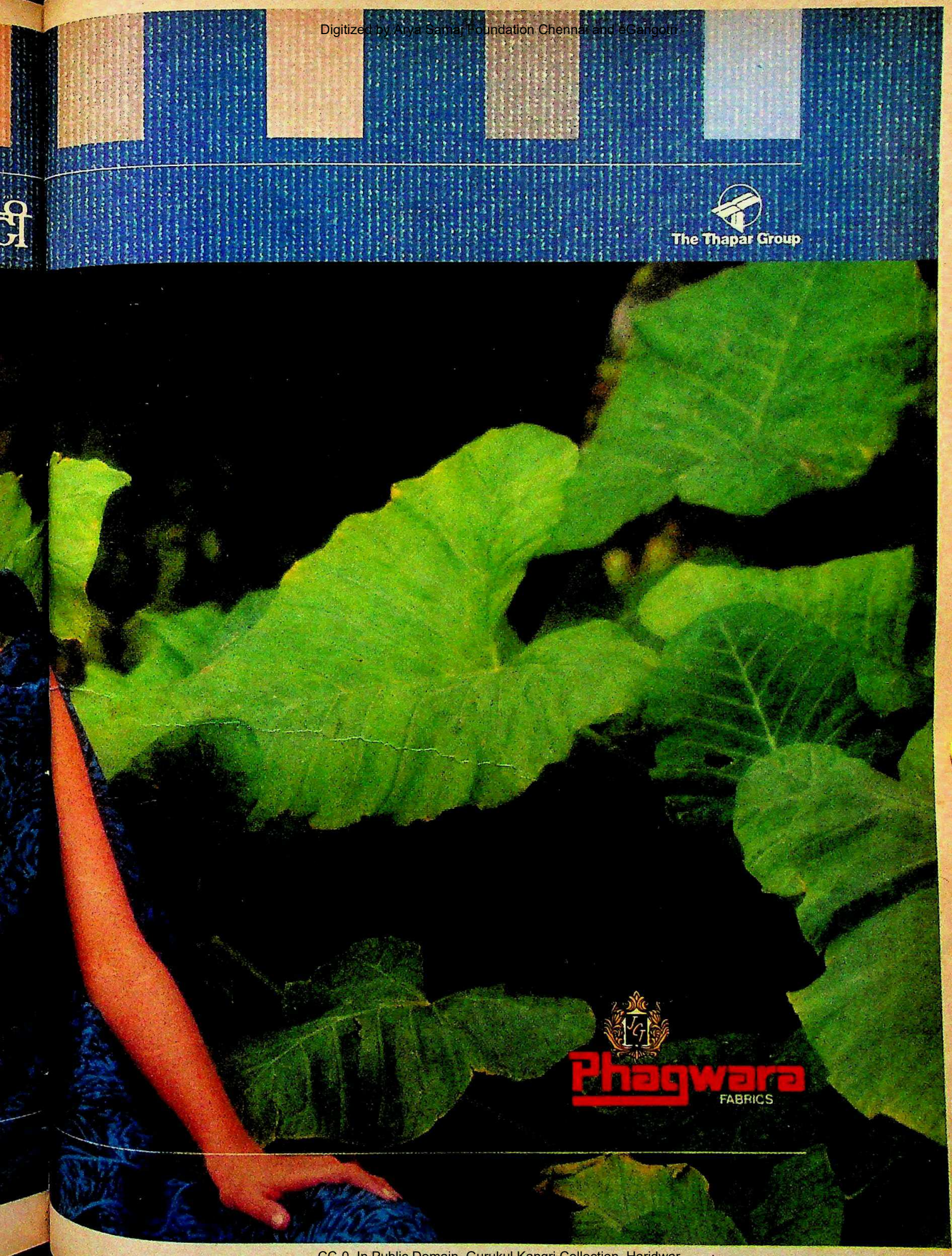

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

स्पारटेक सनसनाता सौंदर्य

खोलिए आपका द्वार और कीजिए स्वागत नये ज़माने की सिरामिक फ़्लोर टाइल की अभिनवता का...!
सेल्फ़-डिज़ाइन सिरीज़ आपके लिए लाए हैं स्पारटेक. आपकी कल्पना में सुंदरता के रंग भरने. खूबसूरत नक्काशीदार टाइल्स की बिल्कुल नई श्रेणी. एक से बढ़कर एक रंग... हलके, सौम्य से लेकर चकाचौंध करते रंगों की बहार.
चाहे जैसे मिलाइए, सजाइए... और फ़र्श पर जादू जगाइए! सेल्फ़-डिज़ाइन सिरीज़ यानी सुविधा और सुंदरता का अनूठा संगम. और सबसे बड़ी बात सौंदर्य की ये सनसनाहट जमी रहे सदा!

स्पारटेक की नई वाली-टाइल श्रेणी का इन्तज़ार कीजिए.

पेश है
सेल्फ़-डिज़ाइन सिरीज़

स्पारटेक
५२, चेमियर्स रोड, मद्रास ६०० ०२८.
भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाले सिरामिक फ़्लोर टाइल्स.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इंडिया टुडे

संपूर्ण समाचार पत्रिका

वर्ष: 2, अंक: 16, 16-30 जून 1988

प्रधान संपादक: अरुण पुरी

वरिष्ठ संपादक: प्रभु चावला

लिविंग मीडिया इंडिया प्रा. लि., एफ-14, कंपिटेंट हाउस, कनाट प्लेस, नई दिल्ली के लिए अरुण पुरी द्वारा संपादित और प्रकाशित तथा थॉमसन प्रेस इंडिया लि. फरीदाबाद , हरियाणा में मुद्रित.

संपादकीय कार्यालय:
लिविंग मीडिया इंडिया प्रा. लि., एफ-14/15, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001. फोन: 331 5801-4, टेलेक्स: 31-61245 INTO IN, तार: लिवमीडिया नई दिल्ली.

मुख्य सर्कुलेशन कार्यालय:
इंडिया टुडे सर्कुलेशन मैनेजर, एफ-14, कंपिटेंट हाउस, कनाट प्लेस, मिडल सर्कल, नई दिल्ली-110001. फोन: 3313076-8, टेलेक्स: 31-62634 INTO IN, तार: सर्कुलेट, नई दिल्ली.

मुख्य विज्ञापन कार्यालय:
28 ए और बी, जॉली मेकर चैंबर-2, नरीमन पाइंट, बंबई-400021. फोन: 2026152, 2029326, 2029435, टेलेक्स: 11-5373 THOM IN, तार: लिवमीडिया बंबई.

क्षेत्रीय विज्ञापन कार्यालय:
के-9, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001, फोन: 3325378, 3323576, 3321323, 3321273; टेलेक्स: 31-62124 THOM IN, तार: लिवमीडिया, नई दिल्ली; फागुन चैंबर्स, 26 कमांडर-इन-चीफ रोड, मद्रास-600105. फोन: 477188, 477770, टेलेक्स: 041-6177 INTO IN, तार: लिवमीडिया, मद्रास; 74/1, सेंट मार्क्स रोड, बंगलूर-560001. फोन: 568448, 579037, 579089, टेलेक्स: 0845-2217 INTO IN, तार: लिवमीडिया, बंगलूर; 12-सी, एवरेस्ट 46-सी, चौरंगी रोड, कलकत्ता-700016 फोन: 445398, 447726, टेलेक्स: 021-3138 INTO IN, तार: लिवइन-मीडिया, कलकत्ता.

कॉपीराइट 1984 लिविंग मीडिया इंडिया प्रा. लि. विश्व भर में सर्वाधिकार सुरक्षित. किसी भी रूप में सामग्री की नकल प्रतिबंधित. इंडिया टुडे अनिमंत्रित प्रकाशन सामग्री को लौटाने की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता.

नेपाल में 8 रुपए

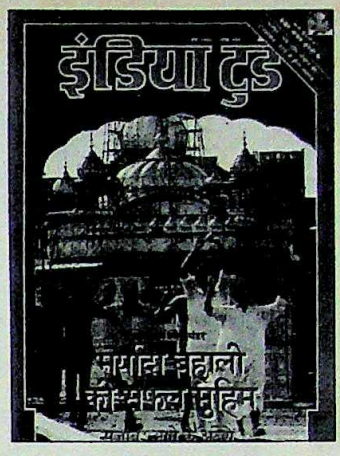

कारगर कार्रवाई

आवरण कथा 'मर्यादा बहाली की सफल मुहिम' (15 जून) में ऑपरेशन ब्लैक थंडर-2 के बारे में विस्तृत जानकारी मिली. इस ऑपरेशन की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि राज्य की शक्ति के आगे आतंकवादी नहीं टिक सकते. आतंकवादियों ने स्वर्णमंदिर परिसर में मल-मूत्र जमा कर, लोगों को यातनाएं देकर, बेकसूरों की हत्या कर आम जनता ही नहीं, खुद सिखों की भी सहानुभूति खो दी थी. 1984 की गलतियों से सबक लेकर जो कार्रवाई की गई वह सराहनीय है.

—रामधारी प्रसाद, नई दिल्ली

■ ऑपरेशन ब्लूस्टार के बाद ऑपरेशन ब्लैक थंडर ने यह सिद्ध कर दिया है कि बारूद के धमाके बारूद के नाद से ही बंद होते हैं. सरकार संदिग्ध आतंकवादियों को रिहा करके, बातचीत चला करके वर्षों बाद भी जो न कर पाई वह कमांडो दस्तों ने कुछ ही दिनों के अभियान में कर दिया और स्वर्णमंदिर को वास्तव में मंदिर बना दिया. भविष्य में स्वर्णमंदिर मंदिर ही बना रहे इसके लिए सुरक्षात्मक व्यवस्था अधिक आवश्यक है, न कि राजनैतिक दांवपेच.

—प्रदीप कुमार, सुजानगढ़ (राज.)

■ भले ही यह सब आगामी चुनावों को ध्यान में रखकर किया गया हो, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि बिना किसी भारी क्षति के आतंकवादियों से स्वर्णमंदिर खाली करवाकर सरकार ने पहली बार आतंकवाद से निबटने का अपना इरादा जाहिर किया है. **—टीना,** सोनीपत (हरियाणा)

■ पंजाब मसले पर विश्लेषणात्मक लेख 'आगे के अंदेशे' में आपने यह तो ठीक लिखा है कि ऑपरेशन ब्लैक थंडर खतरनाक बीमारी का सतही इलाज भर है और इसका स्थायी हल संवैधानिक और राजनैतिक प्रक्रिया से ही निकल सकता है. लेकिन अब सवाल यह है कि उक्त स्थायी हल का स्वरूप क्या होगा, कैसे उसकी शुरुआत होगी, कैसे वह प्रक्रिया चलेगी? इन सब प्रश्नों पर आपने थोड़ा विस्तार से प्रकाश डाला होता तो लेख और ज्यादा सार्थक होता. **—आनंद,** मेरठ (उ.प्र.)

राहत और आशंका

कारोबार स्तंभ के अंतर्गत 'रसोई में राहत' (15 जून) पढ़कर वाकई राहत महसूस हुई कि दिल्ली में दो-तीन साल में पाइप गैस मिलने लगेगी. गैस का सिलिंडर जब दो-दो हफ्ते तक नहीं मिलता तो बहुत कोफ्त होती है. लेकिन सरकारी कामकाज की रफ्तार देखते हुए आशंका यही है कि पता नहीं ये 'दो-तीन साल' कब पूरे होंगे.

—शांति प्रजापति, नई दिल्ली

व्यवहार तो ठीक रहे

'न वे लोग, न वह जमाना' (15 जून) में चाय बागानों के बदलते परिवेश पर आपने रोचक सामग्री जुटाई है. यह सही है कि आज बागान मालिकों को अंग्रेजों जैसी जीवन शैली अपनाने की कोई जरूरत नहीं रह गई है लेकिन काम के प्रति निष्ठा, लगन और मातहतों के प्रति सद्व्यवहार तो वही रहना चाहिए जो अंग्रेजों के जमाने में था. अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती प्रतियोगिता और अन्य क्षेत्रों में नौकरी की बढ़ती संभावनाओं के कारण यह और भी जरूरी हो जाता है. **—निधि,** आगरा (उ.प्र.)

नेक इरादे

'ऊंचे इरादों की कच्ची जमीन' (15 जून) में नवोदय विद्यालयों के बारे में पढ़ा. इसमें कोई संदेह नहीं कि कागज पर यह योजना काफी प्रभावशाली नजर आती है. सरकार के इरादे भी नेक लगते हैं. चाहे मुट्ठी भर ही सही, निम्न तबके के बच्चे भी पब्लिक स्कूलों का अनुभव तो ले सकेंगे. डर बस इसी बात का है कि कहीं इन स्कूलों से निकले बच्चे 'न घर के न घाट के' वाली स्थिति में न रह जाएं. न तो वे निम्न वर्ग से दोबारा जुड़ना चाहें, न ही तथाकथित साहबी संस्कृति में शामिल हो पाएं.

—रुचि, होशियारपुर (पंजाब)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

■ निश्चय ही यह योजना गरीब वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई है. यह शंका कि बच्चा इन स्कूलों के बाद क्या करेगा बेबुनियाद है, क्योंकि यदि बच्चे में प्रतिभा है तो उसे किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलने में दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए. बस शंका यही है कि ये स्कूल कहीं भ्रष्टाचार का गढ़ न बन जाएं.

—कौशल कुमार, लखनऊ (उ.प्र.)

फार्मूलेबाजी से ऊब

आवरण कथा 'कभी शोला, कभी शबनम' (31 मई) पढ़ी. यह कटु सत्य है कि भारत में इतनी फिल्में बनने के बाद भी गिनती की फिल्मों को ही अच्छी और सार्थक फिल्में कहा जा सकता है. ज्यादातर फिल्मों में वही घिसा-पिटा फार्मूला दोहराया जाता है. जो थोड़ी बहुत अच्छी फिल्में बनती भी हैं वे सिर्फ पुरस्कार प्राप्त करने के लिए ही होती हैं. आम आदमी की इनमें कोई रुचि नहीं होती.

—हारिस गजधर, देवास (म.प्र.)

■ हिंदी फिल्मोद्योग के इतिहास पर प्रकाश डालने का यह एक सराहनीय प्रयास रहा. लेख के माध्यम से कई अनबूझ बातें पता लगीं. लेख का आनंद और भी बढ़ जाता यदि आप इसमें के.एल. सहगल , मोतीलाल, अशोक कुमार, राजकपूर, पृथ्वीराज कपूर, दिलीप कुमार, देवानंद जैसे दिग्गजों के बारे में विस्तृत जानकारी देते.

—ईश्वर लाल संगतानी, बालोतरा (राज.)

■ पुरानी फिल्में इसलिए हिट होती थीं कि वे उस समय की नई खोज थीं. उनकी हर चीज लोगों के लिए नई थी, कहानियां अलग-अलग हुआ करती थीं. अब फिल्मों के लगातार पिटने का कारण है— एक जैसी कहानियां, मार-काट और सेक्स.

—विपिन नाहर, कपूरथला (पंजाब)

■ आपने हिंदी फिल्मोद्योग की गहराई में जाकर थाह लेने की कोशिश की है, परंतु उद्योग से जुड़े लोगों के कथनों से सचाई काफी दूर रह गई है. फिल्मोद्योग के मौजूदा संकट के लिए काफी हद तक निर्माता ही जिम्मेदार हैं. आज दर्शक हिंसा, बदला एवं फूहड़ हास्य-व्यंग्यों से ऊब चुका है. दर्शक जिंदगी से जोड़ने वाली फिल्मों को पसंद करता है. पिछले वर्ष आई 'प्रतिघात' इसका ताजातरीन उदाहरण है.

—बृजेश विजयवर्गीय, कोटा (राज.)

■ यह तो मानना पड़ेगा कि अतीत में जो फिल्में प्रदर्शित की जाती थीं उनमें यथार्थ, मर्यादा, भारतीय संस्कृति एवं सुमधुर संगीत का सुंदर सम्मिश्रण रहता था. लक्ष्मण रेखा के अंदर रहकर स्वस्थ मनोरंजन सुलभ होता था. लेकिन आज फिल्मों में मार-धाड़ प्रवंचनात्मक प्रवृत्ति, बलात्कार, हिंसा और उछल-कूद का ही बाहुल्य रहता है.

—जे.एन. मिश्र, लखनऊ (उ.प्र.)

पड़ोसी भी दोस्त नहीं

'कसौटी' के अंतर्गत 'दिग्भ्रमित दृष्टि' (31 मई) में भारतीय विदेश नीति का सही विश्लेषण किया गया है. अफगानिस्तान व पाकिस्तान ही नहीं बल्कि हर देश के संदर्भ में हमारी विदेश नीति असंगत व अप्रभावकारी है. भारतीय विदेश नीति की असफलता का सबसे बड़ा परिणाम यह है कि हमारा कोई घनिष्ठ मित्र नहीं है, सिवाय सोवियत संघ के. यही कारण है कि हमारे सभी पड़ोसी राष्ट्रों से संबंध तनाव-पूर्ण हैं.

—राजीव, इलाहाबाद (उ.प्र.)

चेतावनी काफी नहीं

खास रपट 'भारत-पाक रिश्ते, पल में तोला पल में माशा' (31 मई) पढ़ी. राजीव गांधी ने जिया-उल-हक को पंजाब में 'टांग न अड़ाने' की सख्त चेतावनी दी है. बूटा सिंह ने जिया के इनकार को 'झूठ का पुलिंदा' कहा है. क्या महज इन चेतावनियों व आरोपों से पंजाब में निर्दोष लोगों की हत्याएं रुक जाएंगी. न जाने भारत में कब तक धर्मनिरपेक्षता की आड़ में निर्दोष लोगों की बलि चढ़ती रहेगी.

—महेश व्यास, मारवाड़ (राज.)

■ सरकार को चाहिए कि पाकिस्तान की भारत विरोधी करतूतों के सभी प्रमाणों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर रखकर उसे ऐसा न करने के लिए आगाह करे. फिर भी वह बाज न आए तो सचमुच कड़ी कार्रवाई की जाए. पाकिस्तान के सामने विरोधों की बीन बजाना एवं शिष्टमंडलों की कटोरी में वार्ताओं का दूध पेश करना बिलकुल ही अर्थहीन है.

—संजय पुरवार, झांसी (म.प्र.)

■ एक पाकिस्तानी राजनायिक का कहना कि 'भारत ने पाकिस्तान की ओर हमेशा अपनी सुरक्षा के नजरिये से ही देखा है, कभी राजनैतिक संदर्भों में नहीं देखा', वास्तविकता के उलट है. इसका प्रमाण यह है कि पाकिस्तान ने कई बार सीमाओं का उल्लंघन किया है, गोलीबारी की है, गुप्तचर भेजे हैं, भारतीय अधिकारियों का अपमान किया है. लेकिन भारत ने हमेशा उदारवादी नजरिया अपनाया है.

—नर्बदेश्वर पांडेय, गोरखपुर (उ.प्र.)

जिम्मेदार कौन है

पंजाब के मौजूदा हालात पर आपकी रपट 'मरने मारने का माहौल' (31 मई) आम पाठक को यह सोचने पर मजबूर करती है कि स्वर्णमंदिर परिसर में घटित दर्दनाक हादसों के लिए केंद्र सरकार खुद जिम्मेदार है. ऑपरेशन ब्लूस्टार के बाद स्वर्णमंदिर के अंदर घातक शस्त्रास्त्रों का जखीरा फिर से जमा हो गया तो गलती किसकी है? राष्ट्रपति शासन के बावजूद केंद्र सरकार पंजाब में अमन-चैन लाने के वास्ते कड़े कदम उठाने में क्यों हिचक रही है?

—शिवपूजन तिवारी, उन्नाव (उ.प्र.)

■ इसमें कोई शक नहीं कि पंजाब समस्या को इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए केंद्र ही जिम्मेदार है. 1984 की कार्रवाई के बाद ये हथियार स्वर्णमंदिर कैसे पहुंचे? क्या इसका जवाब सरकार के पास है? साफ है कि सत्ता में बैठे लोगों के सहयोग के बिना यह संभव नहीं.

—राजेश अरोड़ा, मसूरी (उ.प्र.)

यह मामूली पिच नहीं

राज्य-दर्पण के अंतर्गत 'राजनीति की पिच पर' (31 मई) पढ़ा. कीर्ति आजाद अपने पिता की कप्तानी में राजनीति की पिच पर बल्लेबाजी करने उतरे हैं. घरेलू मैदान होते हुए भी बिहार की पिच अपनी अनियमित उछाल के लिए प्रसिद्ध है. लिहाजा अपनी पारी जमाने के लिए उन्हें संभलकर खेलना पड़ेगा क्योंकि क्रिकेट की तरह ही राजनीति में भी आउट होने के लिए सिर्फ एक गेंद ही काफी होती है.

—राजीव, घोसैठ (बिहार)

समयानुकूल कदम

'बूंद से मोती बनाने का अभियान' (31 मई) पढ़ा. खुशी है कि सरकार जागी तो सही. दुनिया के बाकी देशों की तुलना में भारतीय खेलों के स्तर को देखते हुए यह कदम समयानुकूल है.

—शिरीष वाते, इंदौर (म.प्र.)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

NOW YOU HAVE EVEN BETTER REASON TO CHOOSE WILMAN II TWIN-BLADES

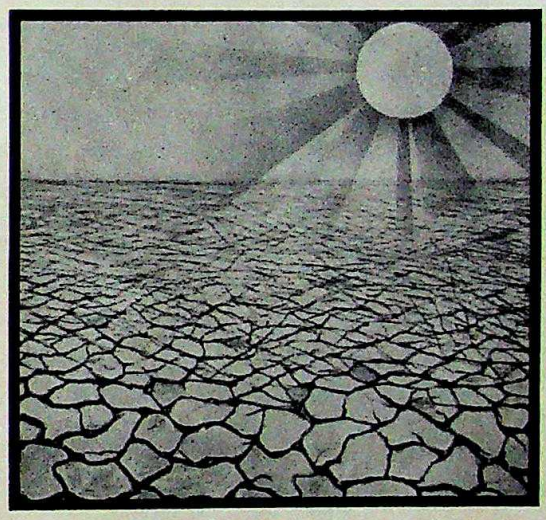

Up to now, you had some pretty good reasons to opt for Wilman II as your shaving system.

The twin advantage that makes sure what one blade misses, the other gets. To give you the closest, smoothest shaves.

The fact that Wilman II is triple-coated for absolute shaving smoothness and more shaves than before.

And the unmatched world-class Wilkinson technology behind it.

Now you have a reason that's even better.

With every Wilman II you buy, you make a small but vital contribution to drought relief.

When you buy a composite pack* of Wilman II (a razor and three twin-blade cartridges) 5% of the revenue earned by the company will go to the Prime Minister's Drought Relief Fund.

That's what makes a Wilman II shave all the more worthwhile.

Because every time you shave with Wilman II, you get the super-smooth feeling.

And the nice feeling of contributing to drought relief.

*Applicable on company sales effected in May and June 1988.

Shave with

Wilman II

world-class twin-blade shaving systems

WILTECH
Leaders in quality
Leaders in twin-blades

Write to Wiltech India Ltd, M G Road, Bangalore 560 001 for a free booklet on shaving tips.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

HTA 8744

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

■ भारतीय खेल प्राधिकरण एवं मारग्रेट अल्वा बधाई की पात्र हैं कि उन्होंने देश के पिछड़े क्षेत्रों से बहुत सारी खेल प्रतिभाओं को ढूंढ़कर प्रशिक्षित कर चमकाया. यदि इसी प्रकार प्रतिभाशाली किंतु साधनहीन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाता रहा तो विश्व खेलों में भारतीय सितारे जगमगाने लगेंगे. —**कंचन नाथ,** जोधपुर (राज.)

ऐसे भी लोग हैं!

'मिथिला में महाभारत' (31 मई) में ललित नारायण मिथिला वि.वि. के कुलपति का अनूठा अभियान पढ़ने को मिला. खुशी हुई कि आज भारत में ऐसे कुलपति भी हैं जो सरकारी मोहरे नहीं हैं. ऐसे ही प्रशासक देश के हर विश्वविद्यालय में होते तो शिक्षा का स्तर शायद इतना न गिरता.

—**त्रिभुवन कुमार वर्मा,** अल्मोड़ा (उ.प्र.)

■ दरअसल इस विश्वविद्यालय को कुछ प्रभावी राजनैतिक तत्व अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए प्रयोग करते आ रहे हैं. विश्वविद्यालय या इससे संबंधित महाविद्यालयों का शायद ही कोई कर्मचारी हो जिसने बिना किसी राजनैतिक पहुंच के अपनी योग्यता के बूते पर नौकरी पाई हो. ऐसी स्थिति में कुलपति द्वारा उठाए गए ठोस तथा क्रांतिकारी कदमों का स्वागत ही किया जाना चाहिए.

—**प्रफुल्ल चंद्र मिश्र,** मधुबनी (बिहार)

भौंडी संस्कृति

'पैसे से प्रतिष्ठा पाने की सनक' (31 मई) लेख बहुत ही सटीक व सामयिक था. इसमें कोई शक नहीं कि आज की अव्यवस्था, अमानवीयता, अराजकता के लिए यह भौंडी संस्कृति ही दोषी है. इंसान को इंसान से दूर करने का काम इस 'पप्पी' संस्कृति ने ही किया है.

—**यतेंद्र कुमार सिंह,** बुलंदशहर (उ.प्र.)

■ पप्पी संस्कृति के खोखलेपन पर लेख छापकर आपने एक सार्थक प्रयास किया है. हो सकता है इस लेख को पढ़कर लोग सुधर जाएं और इस तरह पैसा बहाने से बाज आएं. —**राजेश,** मद्रास (तमिलनाडु)

■ पप्पी लोगों की काले धन से उपजी नई संस्कृति के बारे में पढ़कर मन खिन्न हो गया. यदि ये इस पैसे को इस तरह बहाने के बजाय किसी नई औद्योगिक इकाई या तकनीकी क्षेत्र में लगाएं तो क्या करोड़ों लोगों का भला नहीं होगा?

—**संतोष कुमार कुदेसिया,** मैनपुरी (उ.प्र.)

फासीवाद की ओर

'पराक्रमी पुलिस' (31 मई) पढ़कर लगा कि हम फिर से फासीवादी युग की ओर जा रहे हैं. 'सत्यमेव जयते' की रट लगाने वाली पुलिस किस सच की जीत दिखा रही है, समझ में नहीं आता.

—**रानो राकेश,** हरदा (म.प्र.)

■ यूं तो आए दिन ही 'पुलिस पराक्रम' की घटनाएं सुनने में आती हैं किंतु मध्य प्रदेश की इस शर्मनाक घटना ने तो दिल ही दहला दिया. ऐसी घटनाएं पढ़ने के बाद तो समाचार पत्रों में प्रकाशित किसी भी ऐसे समाचार पर विश्वास नहीं होता जिसमें पुलिस ने अपराधी को धर दबोचा हो.

—**नीना अरोड़ा,** चंडीगढ़

लेख पढ़कर बेहद दुख और ग्लानि हुई कि पुलिस, जिसके प्रति जनता इतना विश्वास रखती है, इतनी अमानवीय व क्रूर हो सकती है. क्या बेकसूर लोगों पर यह अत्याचार प्रजातंत्र के नाम पर धब्बा नहीं?

—**अशोक अत्री,** रोहतक (हरियाणा)

सही विश्लेषण

दक्षिण भारत परिशिष्ट में सिनेमा स्तंभ के अंतर्गत 'बदलते दौर के साथ कदमताल' (31 मई) पढ़ा. दक्षिण भारतीय फिल्मों का आपने जो विश्लेषण प्रस्तुत किया है वह प्रशंसनीय है. दक्षिण के निर्देशक अब यथार्थवादी फिल्मों की ओर मुड़ रहे हैं जबकि पहले सफल हिंदी फिल्मों का 'रीमेक' बना कर पैसा कमाना ही अधिकांश निर्माता निर्देशकों का उद्देश्य हुआ करता था.

—**प्रताप हजारी,** पुणे (महाराष्ट्र)

जान की चिंता नहीं

'हौलनाक हादसे से हड़कंप' (31 मई) पढ़ा. लगता है कि भ्रष्टाचार से लिप्त अधिकारियों के लिए अब मानवमात्र की कोई कीमत नहीं रह गई है. एक दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय ये लोग यदि कुछ रचनात्मक पहल करें तो भविष्य में होने वाली ऐसी दुर्घटनाओं को निश्चित रूप से कम किया जा सकेगा.

—**संजीव श्रीवास्तव,** शुजालपुर सिटी (म.प्र.)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Ha

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कसौटी

ऐसे नहीं होगी शिक्षा में क्रांति

बड़े-बड़े वायदे किए गए थे, ऊंची-ऊंची आकांक्षाएं जगाई गई थीं. शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति कर देने का संकल्प किया गया था. बस दो वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने यह चमत्कार कर देने का विश्वास दिलाया था. गद्दीनशीन होने के बाद राष्ट्र के नाम पहला संदेश देते हुए उन्होंने शिक्षा पर करीब छह मिनट तक भाषण दिया था. और कार्यकाल के प्रथम वर्ष में उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत पर दर्जन भर बड़े भाषण दिए.

एक बार उन्होंने कुछ इस तरह कहा था, "योजना आयोग को शायद लगता है कि मानव शक्ति के रूप में हमारे पास जो संसाधन है उसके विकास की फिक्र करने की जरूरत नहीं. मेरे ख्याल से आयोग को इस मामले पर दोबारा सोचना चाहिए. उसे यह समझना चाहिए कि किसी विकास का पैमाना बांध या बिजलीघर या कारखाने नहीं, वे लोग होते हैं जो उन बांधों का निर्माण करते हैं, कारखानों को चलाते हैं."

रेखाचित्र: अजीत नैनन

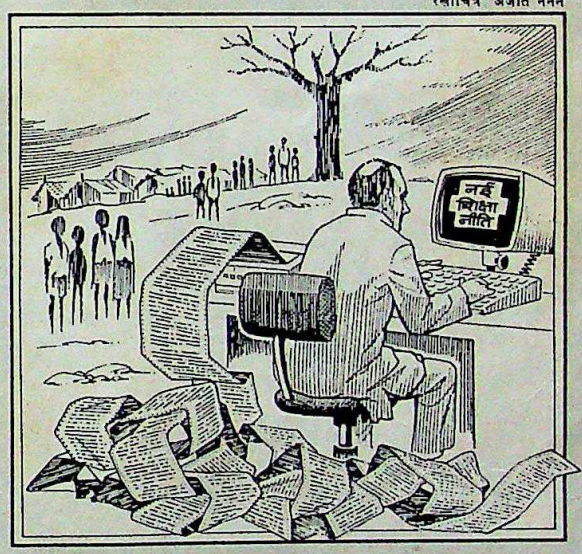

अब राजीव गांधी तो अपनी नई शिक्षा नीति की दुहाई देते हैं, लेकिन उनके मंत्री इससे संबंधित कठिन प्रश्नों पर कन्नी काटने लगते हैं तो यह असफलता की आत्म-स्वीकृति ही लगती है. और इसे असफलता के बजाय अनर्थ कहना ज्यादा उपयुक्त होगा. लेकिन इस नई शिक्षा नीति से सहानुभूति रखने वालों को लगता है कि यह तो अभी शुरुआती दौर में ही है इसलिए उस पर कोई अंतिम टिप्पणी बाद में ही की जाए तो बेहतर. ये लोग यह भूल जाते हैं कि इसे एक ऐसे आपात कार्यक्रम के रूप में लागू करना था जिसके नतीजे शुरू से ही दिखने लगें. दरअसल एक 'कार्य योजना' के तहत 23 विशेष दस्ते बनाए गए थे जिन्हें नई नीति की अलग-अलग व्यवस्थाओं को लागू करने की संभावनाएं तलाशना या उन्हें लागू करने का जिम्मा सौंपा गया था. और फिर इस नीति को उन पुरानी बाधाओं (राजनैतिक इच्छा शक्ति का अभाव या राज्यों का प्रतिरोधी रवैया) का सामना भी नहीं करना पड़ा.

लेकिन यह एक तरह से शुरू से ही फिस्स हो गई. इसके लक्ष्य सातवीं योजना अवधि में पूरे होने के आसार नहीं हैं. यह सब इस कारण हुआ कि वायदे कुछ ज्यादा ही बढ़-चढ़ कर किए गए और परिस्थितियों का सही जायजा नहीं लिया गया. दरअसल इस नीति में कई लक्ष्य तो बेहद विषम थे, मसलन— सभी प्राथमिक स्कूलों के लिए इमारत और मौलिक सुविधाएं मुहैया कराना, शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए राज्यस्तरीय सलाहकार परिषदों, जिलास्तरीय परिषदों, जिलास्तरीय संस्थानों का गठन, व्यापक स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा और हर राज्य में 'आदर्श' विद्यालयों के रूप में नवोदय विद्यालयों की स्थापना.

और आज इस नीति के नाम पर अगर कुछ हो रहा है तो महज लफ्फाजी. पैसे का अकाल है. राजीव गांधी ने एक बार कहा था कि शिक्षा व्यवस्था पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का छह फीसदी खर्च किया जाना चाहिए. लेकिन इस नीति के साथ शुरू से ही फरेब जैसा किया गया. केंद्र ने जब यह घोषणा की थी कि इसके लिए 1987-88 के बजट में 800 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है तो वह महज स्टंट ही था. सरकारी प्रवक्ता ने यह नहीं बताया कि सातवीं योजना की कुल राशि का 3.5 प्रतिशत शिक्षा के मद में खर्च करने का पुराना इरादा रद्द कर दिया गया. और यह भी नहीं बताया गया कि इस नीति को लागू करने के लिए सातवीं योजना में जो 20,000 करोड़ रुपए की राशि तय की गई थी उसे घटाकर 6000 करोड़ कर दिया गया. फिर बजट ने तो इस नीति का मखौल ही बनाकर रख दिया. मसलन ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड पर 2,839 करोड़ खर्च करने की सिफारिश की गई थी. लेकिन बजट में महज 143 करोड़ रुपए इसके नाम पर रखे गए.

और नवोदय विद्यालयों के बारे में जो कहा जाए थोड़ा ही होगा. इसके लिए 500 करोड़ की पिद्दी-सी रकम दी गई. मगर इतने से ही गैर-बराबरी कितनी हो गई! 432 नवोदय विद्यालयों के लिए तो 500 करोड़ रुपए दिए गए जबकि 50 हजार माध्यमिक विद्यालयों पर 100 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं किए जाएंगे. इन माध्यमिक विद्यालयों की खस्ताहाली तो जगजाहिर है ही. इन विद्यालयों में जितने छात्र पढ़ते हैं उसकी तुलना में महज 0.02 फीसदी नवोदय विद्यालयों में पढ़ेंगे. यानी 0.02 फीसदी छात्रों पर तो 500 करोड़ खर्च होंगे और बाकी पर अदना-सी रकम.

अब ऐसे में अगर इस नीति की चुनिंदा वर्ग की हितपोषक नीति कहकर आलोचना की जाती है तो बेजा भी नहीं है. वास्तव में वह विचारों की अस्पष्टता का ही परिचायक है. राजीव सरकार यह तय ही नहीं कर पाई है कि वह कैसी शिक्षा नीति चाहती है. वह साक्षरता के व्यापक प्रसार के लिए सभी लोगों को अनिवार्य प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा के अवसर मुहैया कराना चाहती है या शिक्षा को चंद उन लोगों का विशेषाधिकार बनाना चाहती है जो कंप्यूटर की कसौटी पर खरे उतरते हों?

नई शिक्षा नीति कुल मिलाकर सनक ही लगती है. भारत में जहां हजारों गांव बिना स्कूल के हैं, 50 फीसदी स्कूलों की इमारत ही नहीं है, 40 फीसदी के पास ब्लैकबोर्ड तक नहीं हैं और कुर्सी-मेज या पीने के पानी की सुविधाएं मुहाल ही हैं वहां जरूरत इस बात की थी कि सभी के लिए बेहतर प्राथमिक शिक्षा मुहैया कराने का लक्ष्य रखा जाता और उसे हासिल करने के लिए संकल्प के साथ जुटा जाता. अगर पैसे की समस्या है तो शिक्षा संस्थानों को चंदा देने को उत्सुक कंपनियों पर से प्रतिबंध ढीले करने की संभावनाएं तलाशी जातीं. नारेबाजी की जगह विवेक का प्रयोग ज्यादा उचित और कारगर होगा.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भरिए

यह कूपन और
अपनी चहेती आवाज़ सुनिए:
बच्चे की खिलखिलाहट

हंसी-खुशी और मौज-मस्ती बच्चों के लिए उतनी ही ज़रुरी हैं जितने ज़रुरी हैं खाना-पीना और हवा. और डिस्नी टुडे लेकर आया है यही मस्ती... यही मज़े.
बस तो फिर यह कूपन भर दीजिए और हर एक को खुश कर दीजिए.

आकर्षक छूट का लाभ उठाईये.

कूपन निम्नलिखित पते पर भेजें:
लिविंग मीडिया इंडिया (प्रा.) लि.
सबस्क्रिपशन डिपार्टमेंट
थॉमसन प्रेस बिल्डिंग
पो.बॉ. न० 69, दिल्ली-मथुरा रोड
फ़रीदाबाद - 121 007 (फ़रीदाबाद)

मुझे अपने बच्चे के लिए सबस्क्रिपशन चाहिए. यह रहा मेरा सालाना सबस्क्रिपशन ☐ हिंदी रु. 78/- ☐ अंग्रेजी रु. 96/- प्रति के लिए. मैं भुगतान चैक/मनी आर्डर/डिमांड ड्राफ्ट नं. _____ द्वारा कर रहा हूँ.
कृपया प्रति निम्नलिखित नाम व पते पर भेजें:
नाम _____
उम्र _____ लिंग _____
डाक-पता _____
_____
_____
विद्यालय : _____
माता-पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर _____
कृपया भुगतान लिविंग मीडिया इंडिया (प्रा०) लि० के नाम पर बनाएं.

Walt Disney
डिस्नी टुडे
अब उपलब्ध हर पखवाड़े
हिन्दी और अंग्रेज़ी में

MILESTONES/DT/114 Hin a

© 1987 THE WALT DISNEY CO., USA.

सुधीर तैलंग, नवभारत टाइम्स

● सरकार कहती है कि हथियार पाकिस्तान से आते हैं. पर सीमा से दरबार साहब तक पुलिस की 50 चौकियां आती हैं. सरकार तब क्या करती थी?
■ **जसबीर सिंह रोडे,** *जनसत्ता*

● अमिताभ तो चुनाव लड़ने ही वाले थे मगर दो दिन पहले उन्हें खुफिया ब्यूरो की रिपोर्ट मिली कि मैं भी उम्मीदवार होऊंगा तो उनका हौसला पस्त हो गया.
■ **कांशीराम,** *संडे ऑब्जर्वर*

● किसी को यह पूछने का अधिकार ही मैं नहीं देता कि मैं कहां जाकर सिर झुकाता हूं.
■ **अर्जुन सिंह,** *दिनमान*

● जनता पार्टी में मैंने पाया है कि हर कोई अपनी बात कहने में बिचौलिये का सहारा लेता है.
■ **मेनका गांधी,** *माया*

● मुझे तो नहीं लगता कि मेरे पंख कतर दिए गए हैं. ■ **अजीत सिंह,** *पंजाब केसरी*

● गांधीवाद का ठेका तो ठेकेदारों के पास है और वे सब इंका में हैं.
■ **अशोक सेन,** *नई दुनिया*

● सीधी-सी बात है. नंबर एक बनना है. वरना आप दूसरे नंबर पर हों या आखिरी पर, कोई फर्क नहीं पड़ता. ■ **अरुण लाल,** *स्पोर्ट्सवीक ऐंड लाइफस्टाइल*

● खेलकूद अब व्यापार हो गया है इसके सिवा कुछ नहीं.
■ **विजय अमृतराज,** *स्पोर्ट्सवर्ल्ड*

● पद्मभूषण या पद्मश्री तो मुझे दस साल पहले ही मिल जाना चाहिए था. अब अगर वे मुझे कुछ देते हैं तो पता नहीं मैं इसे मंजूर भी करूंगी या नहीं.
■ **हेमामालिनी,** *फिल्मफेयर*

● जो मेरे खिलाफ बोलेगा मैं उसे पत्थर से जवाब दूंगी. जाकर उस स्वप्ना से कह दीजिए मुझसे न उलझे वरना....
■ **माधवी,** *आज*

● हिंदी फिल्मों में काम करना मुझे घाटे का सौदा लगता है. ■ **कमलहासन,** *धर्मयुग*

● अब बताइए इन आतंकवादी मारधाड़ से भरपूर फिल्मों में शांति संगीत कैसे दिया जाए? इसलिए गाने भी वैसे ही आ रहे हैं 'उठ जा उठ गई, बैठ जा बैठ गई...'
■ **नौशाद,** *नवभारत टाइम्स*

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अब लागू होगी

● पिछले करीब दो साल से इस योजना पर जोरदार बहस चल रही थी. लेकिन अब लगता है कि केंद्र सरकार ने इस बहस पर पूर्ण विराम लगाने का इरादा कर लिया है. वह इसे लागू करने जा रही है. योजना है उत्तर-पूर्व के राज्यों के लिए अलग प्रशासनिक कैडर बनाने की. अब तक यह खटाई में इसलिए पड़ी

सभी कार्टून: अजीत नैनन

हुई थी कि आईएएस अधिकारी इस क्षेत्र के कैडर में जाने को रजामंद नहीं हो रहे थे. जो आईएएस अधिकारी प्रशासनिक मजबूरियों के कारण इस इलाके में किसी तरह भेजे भी जाते, वे अपना अनुबंध पूरा होने से पहले ही राजनैतिक जोड़-तोड़ करके वहां से अपना तबादला करवाकर वापस आ जाते थे.

फिर, उस क्षेत्र में सत्ता पार्टी के लिए राजनैतिक माहौल अब तक माकूल भी नहीं था. इस कारण भी यह योजना ठप पड़ी थी. लेकिन पिछले कुछ वर्षों में एक के बाद एक कई सारे समझौतों के साथ-साथ त्रिपुरा में इंका की सरकार बन जाने की वजह से यह फैसला किया गया कि उत्तर-पूर्व के लिए नया आईएएस कैडर गठित किया जाए जिसमें केंद्रशासित क्षेत्रों के कैडर का विलय कर दिया जाए. यह प्रस्ताव असम के मुख्यमंत्री को छोड़कर उत्तर-पूर्व के सभी मुख्यमंत्रियों ने स्वीकार कर लिया. असम के मुख्य-मंत्री ने इन पदों पर राज्य के अधिकारियों की तैनाती को तरजीह दी. लेकिन केंद्र सरकार ने इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए आवश्यक आदेश जारी कर दिया है और उनके विचार बदलने के लिए उन्हें तैयार करने की भी कोशिश कर रही है.

प्रवक्ता कौन बने

● विदेश विभाग के प्रवक्ता जी. पार्थसारथी का अचानक प्रधानमंत्री सचिवालय में तबादला कर दिया गया. सब कुछ इतनी अफरातफरी में हुआ कि लोग हैरत में हैं. अब साउथ ब्लॉक में उनके उत्तराधिकारी को लेकर अटकलों का बाजार गरम है. विदेश विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कराची में भारतीय वाणिज्यदूत 45 वर्षीय आफताब सेठ को यह पद सौंपा जाना अमूमन तय है. ऐसा हुआ तो इतिहास अपने आप को दोहराएगा. विदेश विभाग का प्रवक्ता बनने से पहले पार्थसारथी भी तीन साल तक कराची में भारतीय वाणिज्यदूत के पद पर रहे थे.

विदेश विभाग के प्रवक्ता का पद ऐसा है जो ख्याति तो दिलाता है, आलोचनाओं का शिकार भी बनाता है. वैसे, सेठ भी पार्थसारथी की तरह मिलनसार और धाराप्रवाह

वक्ता हैं. लेकिन समानताएं केवल इतनी ही हैं. पार्थसारथी जहां नई दिल्ली के सेंट कोलंबा स्कूल के बाद मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़े, वहीं सेठ दून स्कूल में उसी दौरान थे जब राजीव गांधी भी वहां थे. बाद में वे सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़े. केंद्रीय विदेश राज्यमंत्री के. नटवर सिंह भी इसी कॉलेज के विद्यार्थी रहे हैं.

सेनाध्यक्ष हैरत में

● नए थलसेनाध्यक्ष वी.एन. शर्मा ने यह तो सीखा ही होगा कि बिलकुल सपाट, खुली जमीन पर युद्ध कैसे लड़ा जाता है. दूसरे विश्व युद्ध के जमाने में यह रणनीति काफी मशहूर हुई थी. लेकिन व्यक्तिगत जीवन में भी कुछ ऐसी ही परिस्थिति का सामना करना होगा इसकी उम्मीद शायद नहीं रही

होगी उन्हें. और वह भी अपने सरकारी बंगले को लेकर. इस ओहदे पर नियुक्ति के बाद पिछले महीने जब वे नई दिल्ली के रेसकोर्स रोड पर थलसेनाध्यक्ष के सरकारी निवास आर्मी हाउस में पहुंचे तो वहां की हालत देखकर भौंचक रह गए. कुछ सोफे और पलंगों को छोड़ पूरा बंगला बिलकुल खाली पड़ा था. यहां तक कि गुसलखाने से टब भी नदारद था.

पूछताछ करने पर रक्षा मंत्रालय ने काफी हीलाहवाली के बाद स्वीकार किया कि सरकार ने सारा सामान वेलिंगटन भेज दिया है जहां अवकाशप्राप्त सेनाध्यक्ष जनरल कृष्णास्वामी सुंदरजी को विशेष सुरक्षा व्यवस्था वाला बंगला मुहैया कराया गया है. लेकिन मंत्रालय रेसकोर्स रोड वाले बंगले में सारा सामान तुरंत फिर से सजा नहीं पाया. अधिकारी इस सवाल पर चुप हैं कि यह फिजूलखर्ची रोकने के लिए किया गया या लापरवाही की मिसाल है?

बहरहाल, नए सेनाध्यक्ष आर्मी हाउस के बजाय फिलहाल राजधानी में राजपूताना राइफल्स के मेस में रह रहे हैं. यह पहला मौका हैं जब किसी सेनाध्यक्ष को राजधानी में सेना के किसी डिवीजन के मेस में ठहराया गया हो.

शर्मिंदगी की उड़ान

● आस्ट्रेलिया में काफी शर्मिंदगी उठाने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एअर इंडिया की सिडनी, आस्ट्रेलिया की उड़ानों की जांच-पड़ताल शुरू की है. एअर इंडिया पर आरोप था कि उसने जानबूझकर आस्ट्रेलिया की अपनी उड़ानों में क्षमता से ज्यादा सवारी ढोई और सबूत छिपाने की भी कोशिश की.

जब ये आरोप लगे कि 12 साल तक के बच्चों को शिशु बताकर अपने माता-पिता की सीट में ही यात्रा करने की इजाजत दी गई तो आस्ट्रेलिया के यातायात विभाग ने इसकी छानबीन शुरू की. तीन साल तक के बच्चे तो अपने माता-पिता की गोद में बैठकर यात्रा कर सकते हैं. लेकिन इससे ऊपर के बच्चे अलग टिकट पर ही.

जब पहली बार आरोप लगे तो आस्ट्रेलिया ने टेलेक्स से भारत

सरकार को संदेश भेजा कि वह मामले की जांच-पड़ताल करे. जब तकादों का भी भारत सरकार पर कोई असर नहीं हुआ तो महीनों बाद आस्ट्रेलिया सरकार ने खुद जांच-पड़ताल शुरू कर दी. उसने सिफारिश की है कि एअर इंडिया को सिडनी में तैनात अपने एअरपोर्ट प्रबंधक के खिलाफ तुरंत कोई कार्रवाई करनी चाहिए.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अंडे के खिलाफ झंडे

■ बेचारा अंडा उन गिनी-चुनी चीजों में से है जो अपने जन्म से ही विवादों के सैंडविच में फंसकर रह जाती हैं. अंडे के तो पैदा होने का मुद्दा तक ऐसे चिपचिपे आमलेट में फंस चुका है कि सदियों बाद भी

सभी कार्टून: अनिल शर्मा

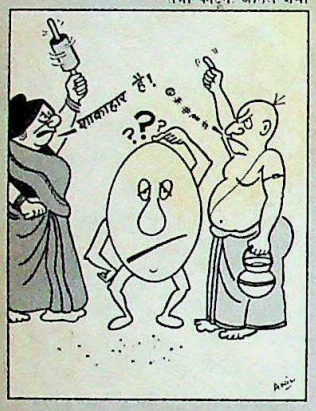

लोग यह तय नहीं कर पाए हैं कि पहले अंडा पैदा हुआ या मुर्गी? शायद बेजुबान अंडे के इस कदर विवादग्रस्त होने का ही परिणाम है कि हर देश और काल में आपसी विवाद में उलझे लोगों ने इसे एक दूसरे पर फेंकने के लिए प्रक्षेपास्त्र के रूप में बेमिसाल इस्तेमाल किया है. इस टकराव में फेंकने वालों का निशाना भले ही सटीक रहा हो या न रहा हो पर हर बार बेचारे अंडे का मलीदा जरूर निकलता रहा है.

पर पिछले दिनों मध्यप्रदेश के कुछ इलाकों में सुलगती आग को देखते हुए लगता है कि बेचारे अंडे की जान के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए लोग उसे विवादों की नई भट्ठी में झोंकने जा रहे हैं. देश के अंडा उत्पादकों (मुर्गियों नहीं, मुर्गी-खाना मालिकों) के संघ ने अंडे की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए रेडियो पर जो अभियान शुरू किया था उसके खिलाफ सतना के कुछ धार्मिक संगठनों ने जेहाद छेड़ दिया है. धर्म के नाम पर अंडे के खिलाफ झंडा बुलंद करने वालों की आपत्ति है कि मुर्गीखाने का अंडा शाकाहार नहीं बल्कि मांसाहार है. उन्होंने मांग की है कि अडे को शाकाहार बताने का प्रचार बंद किया जाए. अब देखना यह है कि अंडा किसके डंडे से हलाल होता है—बेचारा अंडा!

हाजत के लिए पास

■ मानव सभ्यता के विकास की अब तक की जो परिणति हुई है इसका एक नतीजा यह है कि आदमी की पहचान उसकी शख्सियत से नहीं बल्कि 'पास' और परिचय पत्र से होने लगी है. सरकारी भवनों में जाने के लिए, नाटक-जलसा देखने के लिए और यहां तक कि अपने ही दफ्तर में घुसने के लिए भी अब छपे हुए पास या परिचय पत्र होना जरूरी होता चला जा रहा है.

लेकिन राजस्थान के श्री-गंगानगर के व्यापारियों ने जैसी पास प्रणाली शुरू की है उसने तो पिछले सारे रिकार्ड ही ध्वस्त कर दिए हैं. इस पास प्रणाली का लक्ष्य किसी व्यापारिक गोपनीयता की नहीं बल्कि बाजार के शौचालय की रक्षा करना है. लोगों ने पिछले दो-तीन साल से बाजार के एकमात्र सार्वजनिक शौचालय का इस कदर अंधाधुंध इस्तेमाल किया कि वह बेचारा किसी के इस्तेमाल के काबिल ही न रहा. हाजत के दबाव से परेशान दुकानदार इस परेशानी को कुछ देर तक तो झेलते रहे पर आखिर-कार उन्होंने इसका रास्ता ढूंढ निकाला. बाजार में चंदा इकट्ठा किया गया और इस पैसे से शौचालय की नए सिरे से सफाई और मरम्मत कराई गई. गंदगी की हालत फिर से न पैदा हो जाए

इसके लिए बाकायदा 'पास' छपवा कर बांटे गए और नियम बना दिया गया है कि केवल उसी व्यक्ति को अपने दबावों से मुक्ति पाने की छूट होगी जिसके पास यह पास होगा.

जायज मांग

■ बच्चों पर स्कूली पढ़ाई का बोझ जिस तेजी से बढ़ता जा रहा है उसका अनुमान दिन-ब-दिन बड़े और वजनी होते जा रहे बस्तों से लगाया जा सकता है. इसे देखकर अब न केवल शिक्षाशास्त्री और

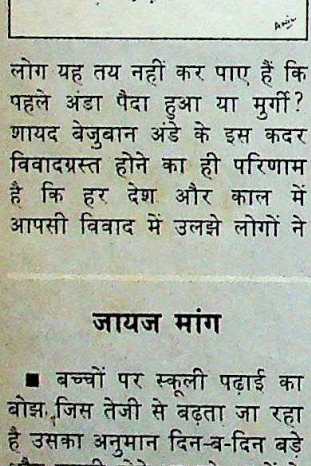

मनोवैज्ञानिक परेशान होने लगे हैं बल्कि यह चिंता राजनीतिकों के मन में भी घर करने लगी है.

हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने पिछले पखवाड़े जिस अभियान की रणभेरी बजाई उसने बच्चों के पीठ के बोझे को फिलहाल भले ही कम न किया हो पर उनके दिल और दिमाग पर छाया बोझ हल्का करने में जरूर कामयाबी हासिल की है. नेता महोदय ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि अगर वह किताबों की संख्या और कीमतें कम करने के लिए कदम उठाने को तैयार नहीं तो उसे यह आश्वासन तो तुरंत देना ही चाहिए कि स्कूल जाने वाले हर बच्चे को अपना बस्ता ढोने के लिए एक-एक गधा मुहैया कराया जाएगा. यह सुझाव उन्होंने खास तौर से पहाड़ी इलाकों में रहने वाले बच्चों की मुसीबतें देखते हुए रखा है. इन इलाकों के बच्चों को अपनी पीठ पर बस्ता लादकर हर रोज कई किलोमीटर पहाड़ी रास्ता तय करना पड़ता है. नेता जी की इस मांग ने जहां राज्य के बच्चों के मन में आशा जगाई है, वहीं गधों के लिए भी एक उज्ज्वल भविष्य की उम्मीद खड़ी कर दी है. वे न सिर्फ अपने भाव बढ़ने की बल्कि हल्के बोझे और बेहतर रोजगार की भी उम्मीद कर सकते हैं.

शादी और सूखा

■ पिछले दो-तीन साल से देश के कई भागों में चल रहे भयंकर सूखे ने न सिर्फ खेती और उद्योगों के लिए संकट पैदा कर दिया है बल्कि बेचारे कुंआरे युवकों को भी अपनी चपेट में बुरी तरह फंसा लिया है.

आंध्र प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां सूखा एक शाश्वत व्यथा बन गई है. इन जिलों में ऐसे गांव हैं जहां की महिलाओं को पीने का पानी लेने के लिए घर से दो तीन किलोमीटर दूर जाना पड़ता है. वहां के कुरनूल जिले के रंगापुरम की हालत तो और भी दयनीय है. पीने के पानी का निकटतम स्रोत वहां से सात किलोमीटर दूर है. इस कारण गांव का नाम ही 'मीलू लेनी रंगपुरम' यानी जलविहीन रंगपुरम पड़ चुका है. गांव की इस "प्रसिद्धि" का खामियाजा अब वहां के कुंआरे युवकों को भरना पड़ रहा है क्योंकि राज्य में लड़की का रिश्ता खोजने वालों ने अब लड़का ढूंढने के मानदंडों में फेरबदल कर दिया है. लड़का ढूंढते समय उसके चाल-चलन, पढ़ाई, नौकरी और घर-परिवार पर जितना ध्यान दिया जाता है, अब उतना ही ध्यान इस बात पर भी दिया जाने लगा है कि लड़के के घर जाने के बाद उनकी बेटी को पानी लेने कितनी दूर जाना पड़ेगा.

नतीजा यह है कि ब्याह के लिए

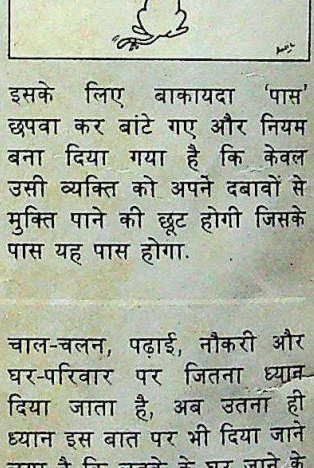

उतावले लड़कों ने या तो ऐसे इलाकों में रहना शुरू कर दिया है जहां पानी आसानी से उपलब्ध है या फिर जहां कुंआरी लड़कियों की संख्या अच्छी खासी है.

संकलन: विजय क्रान्ति

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मेरे प्यारे भारत,

चुनावों का मौसम जैसे फिर से आ गया है. है कि नहीं? वैसे तो इन्हें उपचुनाव कहा जाता है—मुख्य नाटक के बीच में चलने वाले छोटे-छोटे प्रसंग जैसे, लेकिन महत्वपूर्ण कम नहीं. लेकिन इस बार तो ये ही जैसे मुख्य नाटक बन गए हैं. है कि नहीं? राष्ट्रीय राजनैतिक संदर्भों में देखें (राजीव गांधी को जिसका पर्याय कहा जा सकता है) तो उपचुनाव उतने महत्वपूर्ण नहीं होते. लेकिन राजीव गांधी के लिए कहें (और राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी) तो ये उपचुनाव महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं.

अब तक तो यह साफ हो चुका है कि इस देश में चुनाव भी एक तरह के त्यौहार ही बन जाते हैं. इस बार तो सचमुच ऐसा ही दिख रहा है. 'राजा' और 'शहंशाह' की जंग ने ऐसा ही माहौल बना दिया है. इलाहाबाद शहंशाह की 'रियासत' है या शायद थी? अमिताभ ने इस सीट से इस्तीफा दे दिया था. शायद उसके नीचे लगी आग कुछ ज्यादा ही असहनीय हो गई थी. तब विपक्ष ने एक मैदान तो मार ही लिया था.

नतीजा यह कि इलाहाबाद स्टारविहीन होने के बावजूद स्टार बन गया. इस सबका कुल मतलब यह हुआ विश्वनाथ प्रताप सिंह जीत गए, तो अमिताभ उम्मीदवार हुए बिना हार गए. और यह भी कि विश्वनाथ प्रताप जीत भी गए तो उनकी हार ही होगी. है कि नहीं? क्योंकि एक तो उनकी अंतरात्मा ने उन्हें चुनाव से हट जाने का निर्देश दिया था लेकिन बाद में किसी 'बड़ी' आत्मा की आवाज ने उन्हें एक अदने राजनैतिक प्रतिद्वंद्वी से लोहा लेने को मजबूर भी कर दिया. अब इलाहाबाद प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है. तमाम तोपें उसकी ओर मुखातिब हैं. हां, बोफोर्स भी. अंब वहां हो यह रहा है कि कांग्रेस जैसी दबंग पार्टी एक निहायत कमजोर मोहरे पर दांव लगाए हुए है. इधर विश्वनाथ प्रताप दुपहियों पर दौड़ते फिर रहे हैं. और तीसरा उल्लेखनीय उम्मीदवार भिक्षाटन करता घूम रहा है और नारे लगा रहा है कि उसे 'आपका नोट भी चाहिए और वोट भी'.

सभी कार्टून: मंजुला पद्मनाभन

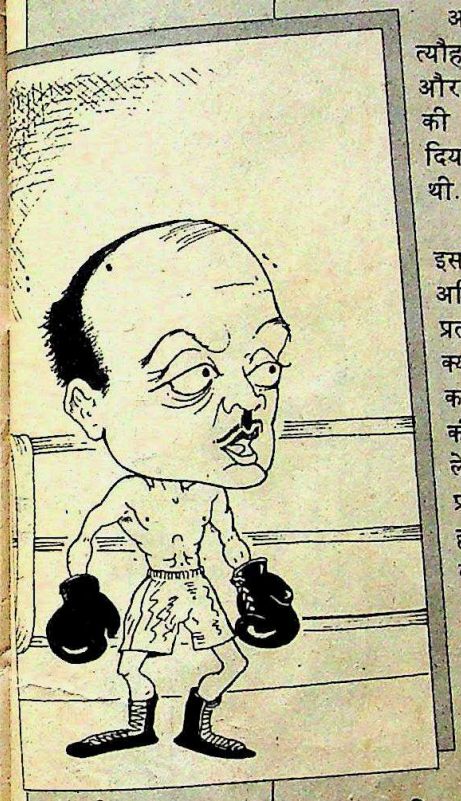

विश्वनाथ प्रताप सिंह की अंतरात्मा ने तो उन्हें चुनाव से हटने की सलाह दी थी पर किसी और 'बड़ी' आत्मा ने उन्हें लड़ने को मजबूर कर दिया

अमिताभ यानी शहंशाह की गैर मौजूदगी के कारण इलाहाबाद की जंग का जलवा ही फीका पड़ गया

बड़ी तोपों में से एक—राजीव गांधी— फिलहाल वहां से गायब है. वे फिर किसी और देश के दौरे पर निकल गए हैं. जाहिर है, विदेश विभाग उनके दौरों और उनके वायदों पर एकदम नजर गड़ाए रखने की कसरत करते-करते दोहरा हो रहा होगा. वे पूरब-पश्चिम के बीच संतुलन बनाने को प्रतिबद्ध दिखते हैं. है कि नहीं? पहले वे पश्चिम जर्मनी और अमेरिका गए थे तो मामला बराबर करने के लिए सीरिया और हंगरी जाना जरूरी हो गया. बाद में वे टोक्यो और वियतनाम हो आए.

बहरहाल, राजीव और अमिताभ दोनों की गैरमौजूदगी के कारण इलाहाबाद की जंग का जलवा ही फीका पड़ गया है. कितना अद्भुत होता कभी अमिताभ के 'शहंशाही' संवादों, तो कभी राजीव के 'हमें देखना है...हमने करी है...' जैसे तकियाकलामों और कभी विश्वनाथ प्रताप के उपदेशों को सुनने का अनुभव हासिल करना!

बहरहाल जो स्थितियां हैं उनके अनुसार तो राजा दुपहिया के बजाय दुलकी चाल से चलें तो भी दौड़ में आगे ही निकल जाएंगे. लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपना चुनाव प्रचार मद्धिम ही रखा है. उन्होंने बड़े पोस्टर छपवाने से मना कर दिया. उन्हें चुनाव चिन्ह भी अस्पष्ट-सा ही मिला. चुनाव प्रचार के तामझाम में वे अमिताभ की बराबरी कर भी नहीं सकते थे और करना भी नहीं चाहते. आखिर विश्वनाथ प्रताप जो ठहरे—प्रतिबद्ध नैतिकतावादी! है कि नहीं?

लेकिन जैसा कि मैंने कहा, विपक्ष और सत्ता पक्ष के लिए यह जंग महाभारत से कम नहीं है. और बीता पखवाड़ा इसी के इर्दगिर्द मंडराता रहा. और तुमने भी देखा ही होगा कि सक्रियता कितनी बढ़ी हुई थी. थी कि नहीं?

—तुम्हारा
दिलीप बॉब

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सभी फोटो: भवान सिंह

देहात में वी.पी. सिंह का काफिला

इलाहाबाद

राजा की अग्निपरीक्षा

कभी तो लगता है कि यहां महाभारत चल रहा है और कभी लगता है कि रामायण की कथा दुहराई जा रही है और कभी-कभी लगने लगता है कि कोई विशुद्ध बंबइया फार्मूला फिल्म चल रही है. यह 'लड़ाई' उन दो 'भाइयों' की युद्धकथा जैसी बन गई है जो अभी चंद दिनों पहले तक एक ही राजनैतिक जमीन पर बांहों में बांहें डाले खड़े नजर आ रहे थे. और दिलचस्प बात यह कि दोनों में से कोई भी दूसरे के खिलाफ बोलना तो दूर, एक दूसरे का नाम तक जुबान पर नहीं लाता. लगता है जैसे वे महाभारत की युद्ध परंपरा और मर्यादाओं के निर्वाह में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते. कुरुक्षेत्र की जमीन पर हुए उस युद्ध में जैसे पांडव निर्वासित थे वैसे ही यहां भी असंतुष्ट पक्ष अपने धूर्त, भ्रष्ट, 'चचेरे भाइयों' से सत्ता छीनने की लड़ाई लड़ रहा है. देश की राजनीति के सारे महारथी इस या उस पक्ष के समर्थन में आ जुटे हैं. और एक 'निर्वासित' राजा भी है जो न सिर्फ अपनी बल्कि पूरे भारतीय समाज की प्रतिष्ठा और नैतिकता की रक्षा के लिए लड़ रहा है.

अपने समर्थकों को राम और अर्जुन दिखने वाले विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा, "आखिर यह सिद्धांतों की ही तो लड़ाई है. इसलिए मेरे और सुनील शास्त्री के भाई जैसे रिश्तों का कोई मतलब नहीं रह गया है. आदर्श और सिद्धांतों के लिए तो आपको अपने सहोदर भाइयों से भी लड़ना पड़ सकता है. महाभारत की याद है न?" इलाहाबाद के लोग याद करते हैं कि सुनील शास्त्री के पिता लाल बहादुर शास्त्री वी.पी. सिंह को किस तरह अपना पांचवां बेटा कहते थे और किस तरह इस पांचवें 'बेटे' ने अपने इस 'पिता' के नाम पर बने ट्रस्ट को अपनी 'अच्छी-खासी जायदाद दान करके पितृ ऋण चुकाया था. और यह संपत्ति भी उन्होंने तब दी थी जब स्व. शास्त्री की पत्नी ललिता शास्त्री को कहीं और से मदद मिलती नजर नहीं आ रही थी.

इलाहाबाद में हो रहे इस चुनावी महा-समर ने उस 'महाभारत' जैसा रूप भले ही न लिया हो, पर यह वी.पी. सिंह और पूरे विपक्ष के लिए जीवन-मरण का सवाल बन गया है तथा सुनील शास्त्री और इंका के लिए अपना 'किला' बचाने की लड़ाई. चरण सिंह के वारिस और जनता पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अजीत सिंह ने कहा, "इलाहाबाद ने अगले आम चुनाव तक राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय कर दी है. इसमें कोई संदेह नहीं रह जाना चाहिए." वी.पी. सिंह जनमोर्चा के

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उम्मीदवार हैं पर उन्हें दक्षिणपंथी भारतीय जनता पार्टी से लेकर वामपंथी कम्युनिस्ट पार्टियों तक का समर्थन प्राप्त है. समर्थन ही क्यों, ये सभी दल उनकी ओर से चुनाव प्रचार में पूरे जोर-शोर से लगे हैं.

निश्चित रूप से यह अब तक हुए सबसे महत्वपूर्ण उपचुनावों में से एक है. इतनी छोटी लड़ाई में इतने बड़े मुद्दे पहले कभी दांव पर नहीं लगे थे. सारा कुछ इस हिंदीभाषी क्षेत्र के आठ लाख मतदाताओं पर टिका है. और पिछले पूरे साल शासक दल से वे जिन मूल्यों और मुद्दों के लिए लड़ते रहे-उन पर जनादेश लेने के लिए वी.पी. सिंह इसी क्षेत्र के लोगों के पास आए. यह उपचुनाव अब उनके लिए सत्ता पार्टी की नीतियों व करतूतों और उसके नेता पर जनमतसंग्रह होगा जिनके साथ अभी हाल तक वे ईमानदारी से काम करते रहे थे. यह चुनाव उनके लिए खुद को चुनाव लड़ने के मामले में शासक दल से पाक-साफ दिखाने की कसौटी भी है. कोई कार नहीं, झंडा नहीं, लाउडस्पीकर नहीं, लाठी नहीं और थैली भी नहीं. यह दावा है उनका.

इलाहाबाद उनके लिए उस यात्रा की शुरुआत है जो उन्हें उस केंद्र तक पहुंचा सकती है जहां से वे अहम भूमिका निभा सकते हैं. उन्होंने बार-बार मतदाताओं से कहा, "मैंने राजीव गांधी से कहा कि आपके दरबार में मेरे लिए न्याय नहीं है. इसलिए मैं न्याय मांगने के लिए अपने घर इलाहाबाद आ गया हूं." उत्तर प्रदेश के धुरंधर मुख्यमंत्री बीरबहादुर सिंह ने कहा, "हमारे लिए यह वी.पी. सिंह को राजनैतिक तौर पर समाप्त कर देने का मौका है." और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के नेता कांशीराम के दावे को भी छोटा करके नहीं आंकना चाहिए जिनका हौसला हरिजनों और पिछड़ी जातियों में अपने बढ़ते असर के कारण बढ़ा हुआ है.

अमिताभ बच्चन की गैरमौजूदगी से भले ही यहां उतना धूम-धड़ाका नहीं हो रहा है लेकिन यहां की मुहिम का राजनैतिक महत्व कम नहीं हुआ है खास तौर से विपक्षी दलों के लिए, जिन्होंने वी.पी. सिंह के चुनाव पर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है. प्रायः सभी विपक्षी पार्टी के नेताओं ने इलाहाबाद में खेमा गाड़ दिया है. और इंका ने भी अपनी 'थैली' और 'लाठी' का भरपूर प्रदर्शन किया है. पार्टी के कोषाध्यक्ष सीताराम केसरी इलाहाबाद सर्किट हाउस में बैठकर पूरे अभियान का संचालन कर रहे हैं जबकि त्रिपुरा में मुश्किल स्थितियों में भी इंका को जिताने की राजनीति बनाने और उसका संचालन करने वाले केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री संतोष मोहन देव परदे के पीछे से शासक दल

इंका की रैली में सुनील शास्त्री

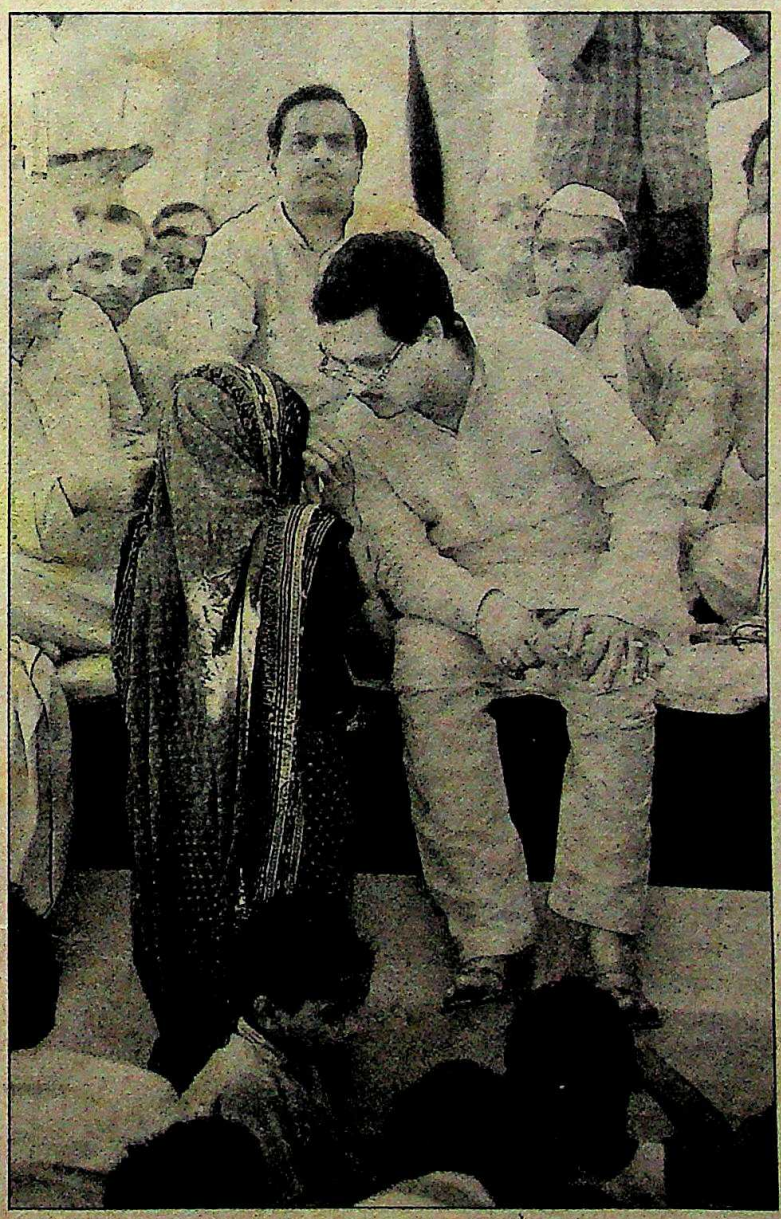

के परस्पर विरोधी गुटों में सुलह करवाने में लगे हैं. ग्रामीण इलाकों में प्रचार का झंडा थाम रखा है बीरबहादुर सिंह ने.

एक वरिष्ठ इंका नेता ने माना, "मैंने दूसरे चुनावों में भी सीताराम केसरी को पैसा बांटते देखा है. लेकिन ऐसी उदारता पहले नहीं देखी थी." दोनों पक्षों ने जहां कहीं से भी थोड़ी मदद मिलने की उम्मीद हुई, वहीं से मदद ली और आखिरकार 'दैवी' सहायता की कोशिश की है इंका ने. उसने टीवी धारावाहिक 'रामायण' में राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल को भी चुनाव मंच पर बुला लिया. गोविल 'रामायण' वाले राम के वेश में ही मंच पर आने वाले हैं और वहां से वे एक तैयार भाषण पढ़ने के बाद सुनील शास्त्री को जीत का आशीर्वाद देंगे.

मगर अंततः इंका की तुलना में विपक्ष का ही ज्यादा कुछ दांव पर लगा है क्योंकि अमिताभ को न खड़ा करके इंका ने पहले ही अपना नुकसान कुछ कम कर लिया है. राष्ट्रीय राजनीति में वी.पी. सिंह की आगे की भूमिका भी यही चुनाव तय करेगा. इसलिए वे भी कोई कसर नहीं रहने दे रहे हैं. 1979 मॉडल की लाल बुलेट मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे वी.पी. सिंह उबड़-खाबड़ सड़कों पर उछलते-कूदते पूरे इलाहाबाद को 'धांग' दे रहे हैं. वे उन गांवों में भी जा रहे हैं जहां चार दशकों में बहुत कम ही चुनाव प्रचारक पहुंच पाए थे. और वे उन्हीं सवालों को उठाते हैं जिनसे उन्होंने राजीव गांधी को परेशान कर रखा था.

वी.पी. सिंह का एक सवाल,
पैसा खाया कौन दलाल?
—जनमोर्चा का चुनावी नारा

वे जिन सवालों को उठाते हैं, उनमें से यह सबसे अधिक परेशानी पैदा करने वाला है और इसे उनके समर्थकों ने नारा ही बना लिया है. उनके चुनाव अभि-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

यान में राजनीति नैतिकता और सिद्धांतों की दुहाई पर आधारित है. गांव-गांव, गली-गली तमाम सभाओं में वे इसी पर जोर दे रहे हैं. वे बार-बार कई बातें दुहराते तो हैं लेकिन उनका अंदाज कुछ ऐसा है कि सब कुछ सीधा वार करता लगता है. वे कहते हैं, "अमिताभ रंगे हाथों पकड़े गए और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा. फिर सरकार का कोई बड़ा आदमी तोप और पनडुब्बी के सौदे में कमीशन खाते पाया गया. मैं यह सब कैसे चलने देता? जब मेरा शरीर जलकर राख हो जाएगा और इस राख को इलाहाबाद की जमीन में बिखरा दिया जाएगा तो मैं अपनी मातृभूमि को क्या जवाब दूंगा? कि मैं नमक-हराम था? मैं आपके पास अपनी और आप सभी के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए आया हूं."

वे बार-बार कहते हैं कि इंका से निकलने से तो उनका निजी नुकसान ही हुआ है, "अगर मैं कांग्रेस में रहता तो आज मुझे गाली देने वाले यही कांग्रेसी मेरा गुणगान करते. इलाहाबाद के बमरौली हवाई अड्डे पर फूलों का गुलदस्ता लिये वे मेरा स्वागत करने के लिए खड़े रहते. लेकिन रक्षामंत्री रहते हुए मैं देश की खातिर सीमा पर लड़ने वाले जवानों के साथ कैसे विश्वासघात कर सकता था?" फिर वे लोगों के मनचाहे प्रसंग पर आते हैं, "कांग्रेस अपने पहलवान अमिताभ बच्चन

वी.पी. के जुमले

■ राजीव गांधी बोफोर्स का दिया ईमानदारी का प्रमाणपत्र दिखाते हैं. यह तो ऐसा ही है जैसे किसी पागल को ठीक होने का प्रमाणपत्र दे दिया जाए और वही शख्स प्रमाणपत्र दिखाते हुए पूछे, "तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम्हारे पास डॉक्टर का प्रमाणपत्र है?" तो अब राजीव गांधी आपसे पूछेंगे, "तुम ईमानदार हो? तुम्हारे पास बोफोर्स का प्रमाणपत्र कहां है?"

■ एक सर्कस के पिंजड़ों में एक शेर, एक सांड, एक घोड़ा और एक बिल्ली बंद थी. एक दिन दरवाजे खुले रह गए. अगले दिन घोड़े और सांड की हड्डियां पड़ी मिलीं. आखिर इन्हें कौन खा गया—शेर या बिल्ली? राजीव सरकार का यही हाल है. करोड़ों रुपए तो शेर ही डकार गया होगा, बेचारी बिल्ली कैसे डकारेगी.

■ हर दिन भारत पर कोई-न-कोई नई मुसीबत आती है. लेकिन आप टेलीविजन पर राजीव गांधी को मुस्कराते हुए ही पाएंगे. आखिर वे क्यों मुस्कराते हैं? अपनी चाल पर, हमारे हाल पर, या स्विट्जरलैंड के माल पर....? एक दिन यह सरकार श्रीलंका में भोजन बरसाती है तो दूसरे ही दिन गोलियां. परमात्मा रक्षा करें.

विपक्ष की रैली में वी.पी. सिंह और अजीत सिंह

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

का ढिंढोरा पीट रही थी. अमिताभ भी चार महीनों से ताल ठोंक रहे थे. और जिस दिन यह पहलवान अखाड़े में आने से कतरा गया, हमारे लिए तो कांग्रेस उसी दिन हार गई.''

नैतिकता पर उनका लंबा भाषण कभी-कभी उबाऊ तो लगता है लेकिन उनकी मंशा पर कोई उंगली नहीं उठाता. उनके चुनाव अभियान प्रबंधक, अमेठी के संजय सिंह ने कहा, ''वे एक जुनूनी आदमी हैं. जरा उनके काम करने का ढंग तो देखिए!'' अपने और अपने समर्थकों के लिए वी.पी. सिंह ने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उनके मद्देनजर उन्हें जुनूनी तो बनना ही पड़ेगा. इलाहाबाद सिविल लाइंस में अपने खंडहरनुमा ऐश महल से वे रोज तड़के मोटरसाइकिल पर निकल जाते हैं. उनके सिर पर बड़ी-सी सफेद पगड़ी होती है. कच्ची सड़कों और बंजर खेतों पर दौड़ती उनकी मोटर-साइकिल के पीछे तीन-चार और मोटरसाइकिलें होती हैं और पुलिस की एक जीप भी. जब वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, तब उनके पास एक जावा मोटरसाइकिल थी. लेकिन पिछले एक महीने में उन्होंने बुलेट से जितनी दूरी तय की है, उतना आज तक वे मोटरसाइकिल से नहीं चले थे. उनकी मोटरसाइकिल चलाते हैं शिरोमणि शुक्ल जो पहले इलाहाबाद युवा इंका अध्यक्ष थे.

चुनाव प्रचार में कार न

शास्त्री के संवाद

■ मेरे पिता लाल बहादुर शास्त्री को लोगों से बेहद प्यार था. जब वे प्रधानमंत्री थे तो इतने व्यस्त रहते थे कि एक बार मैंने उन्हें कई दिनों तक नहीं देखा. एक दिन मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे पिता हैं कि आपके पास अपने बेटे के लिए भी वक्त नहीं है? उन्होंने कहा, "मैं प्रधानमंत्री हूं. अब पूरा भारत ही मेरा परिवार है. मुझे अब करोड़ों लोगों के बारे में सोचना पड़ता है."

■ आजादी के वक्त देश को कोयले का इंजन खींच रहा था. केवल 18 महीनों में लाल बहादुर शास्त्री ने इसे डीजल इंजन में बदल दिया. श्रीमती गांधी ने इसे बिजली का बना दिया. राजीव को इलाहाबाद सौंप दीजिए और यह जेट इंजन में तब्दील हो जाएगा.

■ यह तो इलाहाबाद के लोगों को ही तय करना है कि वे किस रेलगाड़ी से अपना डिब्बा जोड़ना चाहते हैं. 415 हॉर्स पावर वाले इंजन से या पांच हॉर्स पावर वाले से. राजीव गांधी के साथ 415 सांसद हैं जबकि जनमोर्चा के केवल पांच. अगर आप इंका की ट्रेन से जुड़ते हैं तो यह छुक, छुक, छुक दौड़ेगी. लेकिन आप पांच हॉर्स पावर के इंजन से जुड़े तो भुक...भुक...भुक चलेगी.

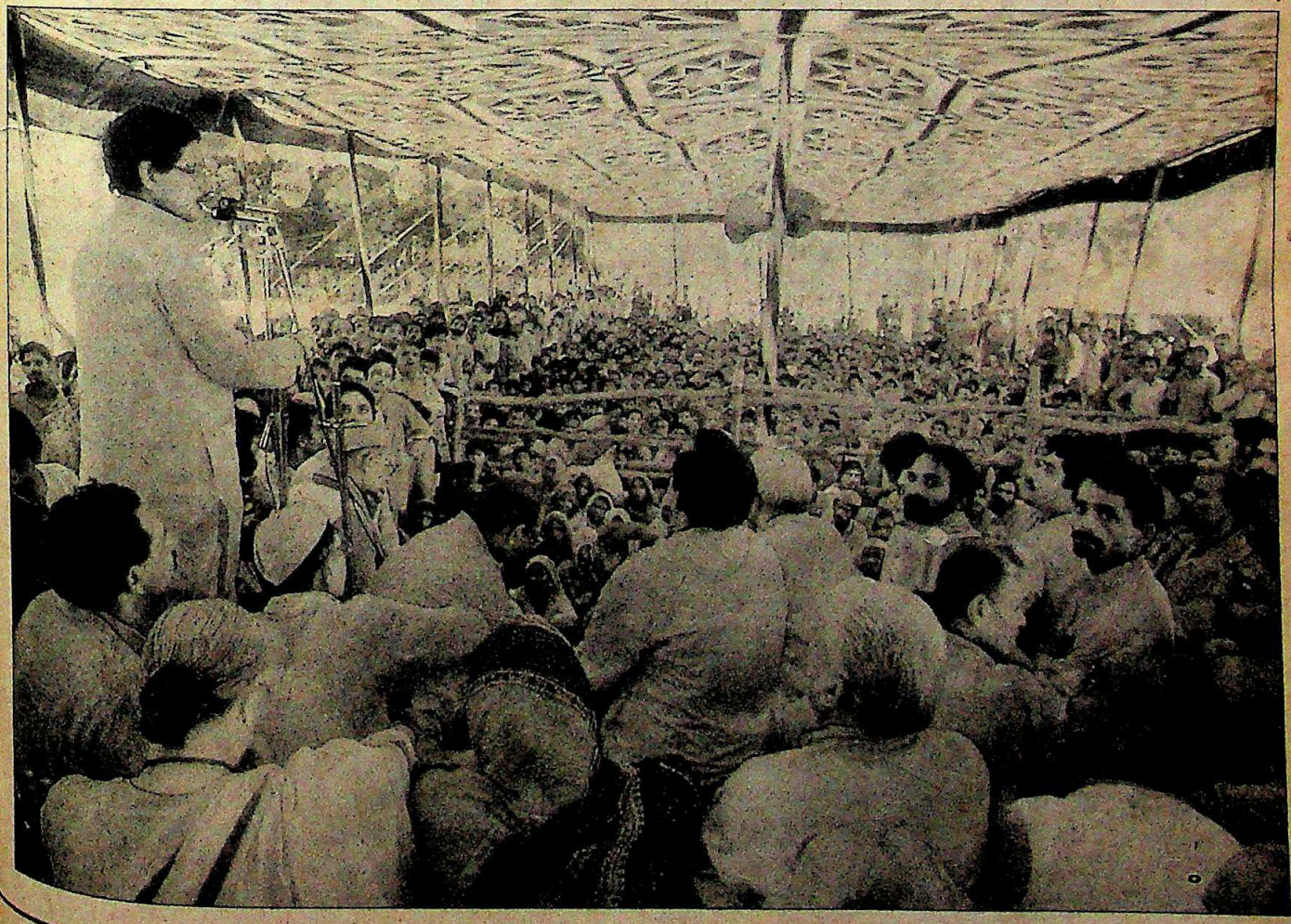

ग्रामीण मतदाताओं को संबोधित करते शास्त्री

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

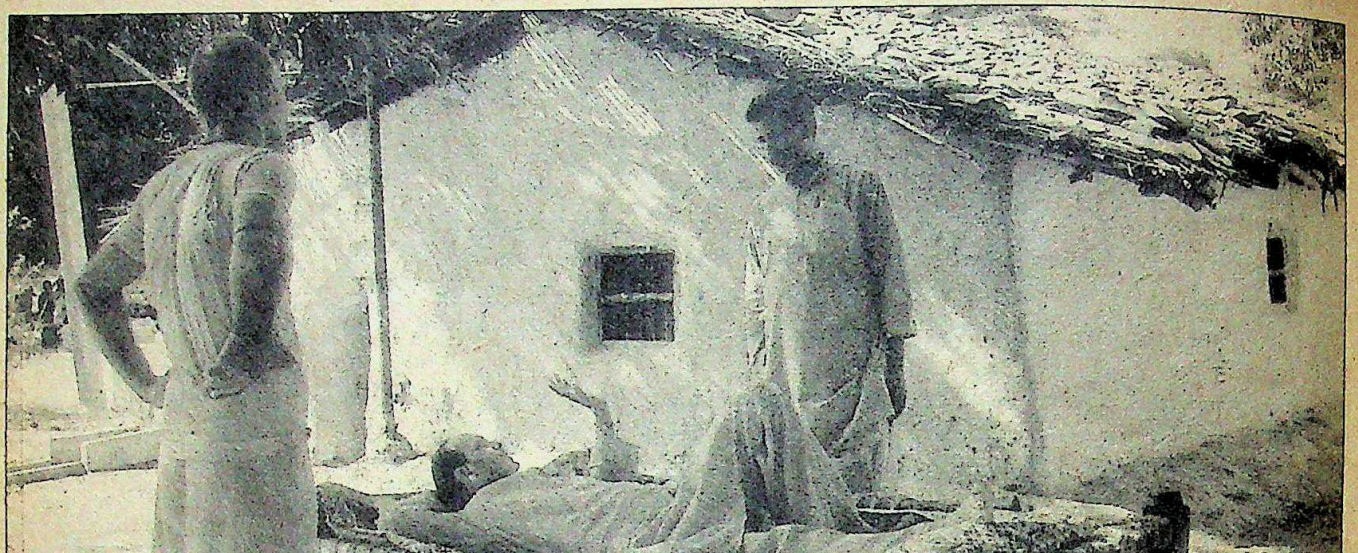

प्रचार के दौरान सुस्ताते वी.पी. सिंह

इस्तेमाल करने के अपने फैसले का वे इतनी कठोरता से पालन करते हैं कि अपने साथ चल रहे पत्रकारों से कहते हैं कि वे अपनी कारों पर प्रेस का लेबल जरूर लगा लें, वरना उनकी कारों को जनमोर्चे के काफिले का हिस्सा न मान लिया जाए. शुरू में तो उन्होंने बाहर से आए विपक्षी नेताओं से भी कार नहीं इस्तेमाल करने का आग्रह किया था. हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल जैसे लोगों को बुढ़ापे में मोटरसाइकिल पर बैठना पसंद नहीं आया. वी.पी. सिंह अक्सर अमराई में, कुएं के पास या किसी भी चौपाल पर खड़े होकर लोगों से बात करने लगते हैं.

भोजन वे रोज दोपहर बाद करते हैं और इसमें आधे घंटे से अधिक समय नहीं लेते. वे सिर्फ एक गिलास दूध पीते हैं और पांच मिनट किसी पेड़ के नीचे झपकी ले लेते हैं. फिर जगकर वे उसी उत्साह से 'आक्रमण' के एक और अभियान में जुट जाते हैं. ऐसे ही एक दिन भोजन के दौरान बातचीत में उन्होंने कहा, "क्या आपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को इन दूरदराज इलाके में प्रचार करते देखा है? वे अगले तीन चुनाव तक यहां नहीं पहुंच सकते."

ऐसी ही एक गरम दोपहर में जब तापमान 45 डिग्री के ऊपर पहुंच गया था, वी.पी. सिंह बारा विधानसभा क्षेत्र के पिछड़े और अक्सर बाढ़पीड़ित हो जाने वाले इलाके में पहुंचे थे. फिर शाम को करमा गांव में एक बड़ी सभा को संबोधित करने के पहले ही वे 15 गांवों का चक्कर लगा आए. चौपाल में सवाल पूछने वालों से वे कहते हैं, "मैं आप लोगों से ट्यूबवेल या नहरों का वायदा नहीं कर सकता. लेकिन मैं इतना भरोसा जरूर दे सकता हूं कि आप जो पैसा टैक्स के रूप में अदा करते हैं उसे चुराकर स्विस बैंक में जमा नहीं करूंगा." क्या ग्रामीण निरक्षर मतदाता आपके द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों को समझते हैं, यह पूछे जाने पर वे नाराजगी के साथ कहते हैं, "वे दिल्ली के बंगलों में रहने वालों की तुलना में नीति और देशभक्ति की बातें ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं." यह कहते हुए उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने प्रशंसकों को अपने पांव धोने से रोका. प्रशंसक लोग उनकी थकान उतारने के लिए आदर के साथ उनके पांव धोना चाहते थे.

उनके जत्थे के अचानक आ जाने से गांववाले अक्सर हैरान रह जाते हैं. मोटरसाइकिल की धूल उड़ती दिखते ही उन्हें उनके आने का अंदाज लग पाता है. वे लोगों को जुटाने में भी माहिर हैं. एक बार वे इलाहाबाद से 15 किलोमीटर दूर मामा-भांजे का तालाब गांव में बीरबहादुर की चुनावी सभा के पास से धीमे से गुजरे और लोग उस सभा से निकल आए और उन्हें घेर लिया. जौनपुर के एक कॉलेज अध्यापक और वी.पी. सिंह के जत्थे के सदस्य जे.पी. सिंह ने कहा, "यह आदमी तो जननेता बन चुका है." लेकिन समाज के सबसे गरीब, अनपढ़ और जातीय भेदभाव में बंटे लोगों ने उनके संदेश को स्वीकार कर लिया है, इस बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी.

उनके कार्यकर्ता नारा लगाते हैं, "राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है." यह उनकी राजसी छवि को गलत बताने की कोशिश ही है. वे खुद भी अपने को माटी का पूत और लाल बहादुर शास्त्री का असली वारिस बताते हैं. उन्होंने कहा, "वे एक महान आदमी थे. कांग्रेस ने ही 22 वर्षों में उन्हें गर्त में धकेल दिया." उनके समर्थक इसे और ठेठ देसी भाषा में कहते हैं, "पार मरी सासु, अब आए आंसू."

मुख्य प्रतिद्वंद्वी तो एक दूसरे पर सीधा हमला नहीं कर रहे हैं, पर उनके समर्थक कोई मर्यादा नहीं मानते. दिसंबर 1984 में अभिताभ से 1.87 लाख वोटों से हारे हेमवती नंदन बहुगुणा ने मतदाताओं को झिड़की दी कि उन्होंने "उस असामान्य चुनाव में देश की राजनीति को पटरी से उतार दिया था." अन्य लोगों को यह राजीव गांधी पर चोट करने का अच्छा मौका लगता है. जनता पार्टी के अध्यक्ष अजीत सिंह ने करमा में नारे लगा रहे लोगों से कहा, "आप राजीव गांधी पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? वे विदेशी भाषा बोलते हैं, विदेशी लिबास में रहते हैं, उनका रहन-सहन विदेशी है, विदेशी जैसा वे सोचते हैं, उनके दोस्त विदेशी हैं, बीवी विदेशी है और अब विदेशी खाता भी."

लेकिन वी.पी. सिंह को ऐसे असुविधाजनक सवालों से कम ही साबका पड़ता है

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उन्होंने शुरू में कहा था कि अगर इंका ने अमिताभ बच्चन को उम्मीदवार नहीं बनाया तो वे भी चुनाव नहीं लड़ेंगे. अब वे चुनाव लड़ने के फैसले को यह कहकर सही ठहराते हैं कि चूंकि वे विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार थे इसलिए उसके प्रति उनकी कुछ जबावदेही बनती थी और अकेले अपने मन से कोई फैसला नहीं ले सकते थे. पोस्टर, बैनर या लाउडस्पीकर इस्तेमाल नहीं करने की उनकी घोषणा से शुरू में उनके समर्थक खीझ गए थे. उनके एक समर्थक ने कहा, "लोगों को सुनाने के लिए नैतिकता की बात करना तो ठीक है लेकिन प्रचार के सामान्य और अच्छे माध्यम के इस्तेमाल में भला क्या अनैतिकता है?"

उनके समर्थकों ने जब उन पर काफी दबाव डाला तो पिछले पखवाड़े उन्होंने अपने चुनाव चिन्ह के पोस्टर और पर्चे छपवाने की इजाजत दे दी. और जल्दी ही इलाहाबाद में उनके पोस्टर भी सभी जगह दिखने लगे. उनके समर्थकों ने 'बोफोर्स द्वार' भी बना दिया था. सड़क पर माइक लगी उनकी कुछ जीपें भी दिखाई दीं, जिससे उनके विपक्षी खेमे के लोगों के चेहरे खिल उठे कि चलो एक मुद्दा तो मिला आलोचना का.

वी.पी. सिंह के प्रचार अभियान का संचालन करने वाले प्रसिद्ध स्तंभकार रजिंदर पुरी ने प्रचार के तौर-तरीकों के बारे में उनके फैसलों को सही बताया और उनकी तुलना महात्मा गांधी द्वारा प्रतीक के तौर पर रेल के तीसरे दर्जे में चलने से की. लेकिन आलोचकों को लगता है कि 'नैतिकता के लिए उनका जुनून और आक्रामकता की हद तक पहुंचा उनका आत्मविश्वास' ही उन्हें मुसीबत में डाल सकता है. वे कहते हैं कि वी.पी. सिंह की भावनात्मक अपील तो अपनी जगह है, लेकिन जातीय गणित उनके खिलाफ ही है. वैसे अभी इलाहाबाद में कांशीराम के सिर्फ जातिवादी प्रचार के बावजूद कोई जातीय विभाजन नहीं दिखता है. फिर, इलाहाबाद में चुनाव का कांग्रेसी रिकार्ड बहुत अच्छा रहा है. वह यहां से दस में से आठ बार जीत चुकी है. और फिर उनका 'दंभी' व्यक्तित्व, इंका उम्मीदवार की साफ छवि और चुनाव के मौके पर शासक दल द्वारा विकास के नाम पर दिए गए पैसों के कारण इलाहाबाद वी.पी. सिंह के लिए चक्रव्यूह साबित हो सकता है. बीरबहादुर सिंह ने कहा, "हमने उन्हें फंसा दिया."

शत्रु फंसा शिकजे में
मोहर लगाएं पंजे में
—इंका का नारा

शुरू में तो ऐसा लगा कि अमिताभ बच्चन को इलाहाबाद चुनाव में न उतारकर इंका ने इस लड़ाई में बिना लड़े ही हार मान ली है. लेकिन प्रचार अभियान गरमाने के साथ ही हालात बदलते गए. लाल बहादुर शास्त्री के 38 वर्षीय पुत्र सुनील शास्त्री ने अपनी स्वच्छ छवि का सिक्का जमाया. उन्हें जितना कमजोर उम्मीदवार माना गया वे उससे मजबूत लगे. साथ ही चुनाव प्रचार आगे बढ़ने के साथ उनमें कुछ आत्मविश्वास बढ़ता भी नजर आया वरना वे नामांकन भरने के बाद भी अपने को 'डमी' उम्मीदवार ही मान रहे थे. आलाकमान के इशारे पर बीरबहादुर ने भी अपना सारा जोर लगा दिया.

पार्टी की रणनीति तीन स्तरीय दिखी. वी.पी. सिंह को पहले तो धोखेबाज और पाखंडी बताया गया. शास्त्री को स्वच्छ छवि वाला नौजवान और लाल बहादुर शास्त्री का उत्तराधिकारी बताया गया. और इंका ने बार-बार प्रचारित किया कि इस क्षेत्र का विकास शास्त्री की जीत से ही जुड़ा हुआ है.

चुनाव के मौके पर बीरबहादुर ने इस इलाके के विकास

'बसपा' के बोल

■ मुस्लिम, ईसाई और शूद्र भारत के मूल बाशिंदे थे. उसके बाद बाहर से हिंदू यहां आए और उन्होंने मूल बाशिंदों को गुलाम बना लिया. उन्हें मूर्तियों व जानवरों की पूजा करने को बाध्य कर दिया. गुलामी तोड़ने का अब वक्त आ गया है. बाइबिल में ईसा ने कहा है, "अन्याय और गुलामी को दूर करना ही सच्ची साधना है..."

■ ऊंची जाति वाले हमारे साथ जानवरों जैसा सलूक करते आए हैं. शिवाजी का राजतिलक भी कोई ब्राह्मण करवाने के लिए आसानी से राजी नहीं हुआ क्योंकि वे शूद्र थे. आज भी ऊंची जाति वाले हमारा आदर न करते हैं, न करेंगे.

■ उत्पीड़ितों को अपने अत्याचारियों से हिसाब बराबर करने का पूरा हक है. बेअंत और सतवंत ने महसूस किया कि ऑपरेशन ब्लूस्टार से इंदिरा सरकार ने उनके समुदाय का अपमान किया. इसलिए उन्होंने बदला लिया.

वोट व नोट मांगते कांशीराम

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

के लिए 80 करोड़ रुपए की योजना मंजूर की. पानी की कमी वाले गांवों के लिए 2000 नए चापाकल मंजूर किए गए. हर चुनाव सभा में बीरबहादुर आगे बैठते और लोगों के तबादले, प्रोन्नति, कर्ज की मांग वाली अर्जियों पर दनादन दस्तखत करते देखे गए. एक बार यह तमाशा तो इतना बढ़ गया कि खुद कांग्रेसी लोग भी परेशानी महसूस करने लगे. ब्राह्मणों के नेता और इंकाई चुनाव अभियान चलाने वालों में प्रमुख के.पी. तिवारी को भी एक बार लोगों से कहना पड़ा कि वे और अर्जियां लेकर न आएं क्योंकि मंच पर यह सब अच्छा नहीं लगता.

लेकिन शासक दल जब अपने असली रंग में आता है तो उसे नैतिकता की कोई फिक्र नहीं रह जाती. उन्होंने हर सभा में वी.पी. सिंह को धोखेबाज, सीआईए का एजेंट कहा और यह नारा भी दिया कि 'राजा नहीं गद्दार है, सीआईए का सरदार है.' इलाहाबाद के विधायक अशोक वाजपेयी ने आरोप लगाया कि वी.पी. सिंह ने अपने बेटे को (अमेरिकी) सिटी बैंक में नौकरी दिलवाकर देश के साथ गद्दारी की है. उन्होंने कहा, "हमारे समाज में परिवार और संतान ही असली धन होता है और वी.पी. सिंह ने अपने और राष्ट्र की संयुक्त संपत्ति, अपने बेटे को महज 80,000 रुपए महीने के लिए अमेरिका भेज दिया."

कांशीराम का अभियान सबसे जोरदार रहा. उनके नीले झंडे हर कहीं फहराते दिखे और पूरे चुनाव क्षेत्र में हर कहीं दीवार पर उनका चुनाव चिन्ह हाथी बना दिखा

मेजा विधानसभा क्षेत्र के उरुवा में हुई एक सभा में अशोक की मां और केंद्रीय कल्याण राज्यमंत्री राजेंद्र कुमारी वाजपेयी समेत अन्य नेताओं ने भी यही बातें दोहराईं. छुटभैये तो और आगे बढ़ गए. एक ने कहा, "बी.पी. सिंह के मासूम चेहरे और मीठी बातों पर मत जाइए. यह बहुत बड़े धोखेबाज की निशानी है." दूसरी ओर इंका अपने निर्दोष चेहरे वाले उम्मीदवार शास्त्री के लिए अक्सर ये पंक्तियां दोहराती रही—'गोरे, गोरे गाल हैं, घुंघराले बाल हैं, कितने सुंदर लाल हैं.'

शास्त्री अपने रूप की बात तो नहीं करते, पर महान पिता के उत्तराधिकारी होने की बात जरूर करते हैं. उनके भाषण में ज्यादातर तो स्वर्गीय पिता का गुणगान ही होता है. दरअसल अभी तक के अपने छोटे राजनैतिक जीवन में भी उन्होंने जो कुछ पाया है उसमें उनका 'शास्त्री जी का बेटा' होना महत्वपूर्ण कारण रहा है. इलाहाबाद में उन्हें इंका का टिकट भी मुख्यतः इसी कारण से मिला. अपने पिता का प्रिय नारा 'जय जवान, जय किसान' तो पता नहीं कितनी बार वे दोहराते हैं. उन्होंने अपने प्रचार अभियान के लिए गीत भी तैयार किए. अधिकांश गीत 'आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की' की तर्ज पर हैं. लेकिन वे वी.पी. सिंह का नाम कभी भी अपनी जुबान पर नहीं लाते.

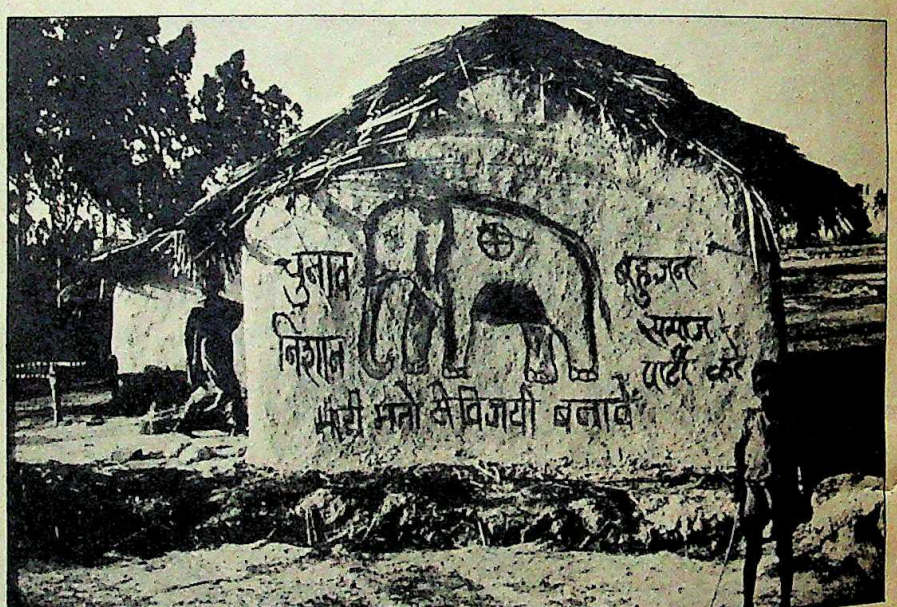

चुनाव मैदान में एक दूसरे के खिलाफ उतरे उम्मीदवारों में एक दूसरे के लिए इतना आदर और इतनी शालीनता आश्चर्यजनक ही है. दोनों यही कहते हैं कि उनकी लड़ाई व्यक्तिगत न होकर सैद्धांतिक है. लेकिन ये बातें शास्त्री के लिए कुछ उलझन भरी ही हैं क्योंकि उनके पुराने पारिवारिक मित्र के खिलाफ आज उनके सबसे बड़े दुश्मन बीरबहादुर उनके ही खेमे में हैं.

पिछले साल ही शास्त्री ने बीरबहादुर को धोखेबाज कहते हुए उनके मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था. फिर मुख्यमंत्री और शास्त्री ने एक दूसरे को खूब गालियां दी थीं. शास्त्री तो वी.पी. सिंह के जनमोर्चा में भी शामिल होने वाले थे और उन्होंने वी.पी. सिंह के साथ कुछ कांग्रेस विरोधी सभाओं में हिस्सा भी लिया था. लेकिन बाद में बड़े भाई और इंका सांसद हरिकृष्ण शास्त्री के कहने पर उन्होंने पाला बदल दिया.

अब शास्त्री और बीरबहादुर सिंह इस मामले पर कुछ कहने से कतराते हैं. शास्त्री कहते हैं कि निजी रिश्ते तो बाद में, पहले तो हम एक ही पार्टी के सदस्य और साथी हैं. बीरबहादुर का जवाब इतना संयत नहीं होता. वे कहते हैं, "वह अध्याय समाप्त हो चुका है. आप प्रेस वाले लोग उस लकीर को कब तक पीटते रहेंगे?"

बीरबहादुर के इतना उत्तेजित होने के कारण भी हैं. उनका राजनैतिक भविष्य इलाहाबाद चुनाव के नतीजे पर टिका है. उपचुनाव को गंभीरता से नहीं लेने के लिए राजीव गांधी ने उन्हें झिड़का था. अनेक राजनैतिक संकट झेल चुके बीरबहादुर जानते थे कि यह चुनाव उनके लिए अग्निपरीक्षा है. शुरू में सुनील शास्त्री को वी.पी. सिंह से भिड़ा कर उन्होंने दोहरा दांव खेला था. लेकिन अब सुनील की हार का मतलब उनके भी हक में बहुत अच्छा नहीं होगा.

इसलिए उन्होंने अपना सारा जोर लगा भी दिया है. एक तरह से वे इलाहाबाद से ही शासन चला रहे हैं. बीच में कभीकभार रात में वे राज्य सरकार के विमान गरुड़ से लखनऊ चले जाते हैं. इस चुनाव ने उनके लिए कुछ खास मुश्किलें भी पैदा कर दीं. प्रदेश के एक वरिष्ठ इंका नेता ने कहा कि "वे अजीब मुश्किल में फंस गए हैं. वी.पी. सिंह की जीत उन्हें समाप्त कर देगी. और अगर शास्त्री जीते तो राज्य में एक नए राजनैतिक सितारे का उदय हो जाएगा जिनसे उनकी पटती नहीं." लेकिन उनकी बुनियादी चिंता चुनाव जीतने और वी.पी. सिंह के आतंक को समाप्त करने की है. बीरबहादुर ने कहा, "वे गद्दार हैं, विदेशी ताकतों से हेलमेल करने

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वाले दोहरे चरित्र के आदमी हैं. हमें देखना है कि उनके साथ हमें क्या करना है." और इसके साथ ही उन्होंने गंभीर मुद्रा में कहा, "हमें देखना है, हम देखेंगे."

वोट हमारा, राज तुम्हारा
नहीं चलेगा, नहीं चलेगा
—बहुजन समाज पार्टी का नारा

लेकिन देखने के लिए चुनौती बन गए हैं बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार कांशीराम. हरिजनों और पिछड़ी जातियों के स्वघोषित मसीहा कांशीराम चुनाव मैदान में क्या उतरे कि चुनाव का पूरा जातीय गणित

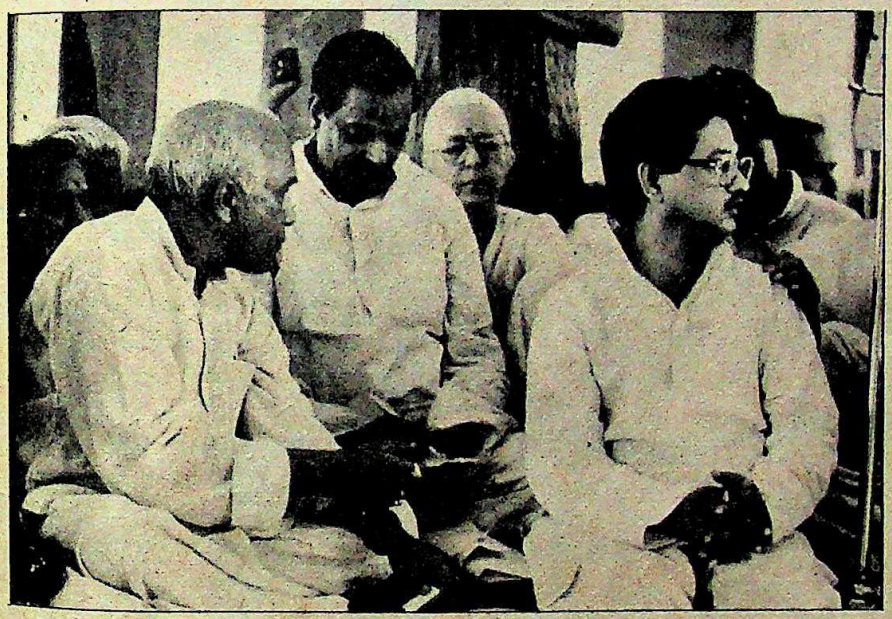

गड़बड़ा गया. यह स्पष्ट है कि उनकी बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस के हरिजन वोट बैंक में सेंध लगाएगी और वी.पी. सिंह को मिलने वाले यादव और कुर्मी वोट भी तोड़ेगी.

वी.पी. सिंह और शास्त्री को 'बसपा' के उक्त नारे में दम नजर नहीं आता लेकिन इसने बड़ी तेजी से पिछड़ों को प्रभावित किया और नारा देने वाले को चुनावी दौड़ की अगली कतार में ला खड़ा किया. इलाहाबाद के उपचुनाव में महत्वपूर्ण पक्ष बहुजन समाज पार्टी भी बनेगी, यह कांशीराम के नामांकन पत्र भरने के पहले तक कोई नहीं मान रहा था.

54 वर्षीय कांशीराम और उनकी पार्टी का कहना है—हरिजनों, अन्य पिछड़ी जातियों के लोगों और अल्पसंख्यकों की संख्या 85 फीसदी है तो फिर उन पर ब्राह्मण और ठाकुर कब तक राज करते रहेंगे? विवेकवान लोग तो इस गणित में यकीन नहीं करते पर जिन लोगों को बड़ी जातियों के जुल्म का शिकार होना पड़ा है उनको कांशीराम मसीहा लगते हैं और उनका हर दावा शाश्वत सत्य.

कांशीराम का एक ही नारा है जिसे वे कड़वे पर प्रभावशाली तरीके से कहते हैं, "आजादी के 40 वर्ष बाद भी आप सभी लोगों की जानवरों वाली हालत है. आपके लिए आदमी बनने का मौका यही है. एकजुट होकर बड़ी जातियों का दबदबा खत्म कीजिए." हाल में हुए कई चुनावों में इसी नारे ने उनकी पार्टी को काफी वोट दिलवाए हैं. अगर इलाहाबाद के तिकोने मुकाबले में उन्हें इसी तरह से वोट मिले तो इसका मतलब होगा वी.पी. सिंह की पराजय, शास्त्री को तीसरा स्थान. इलाहाबाद के एक तिहाई मतदाता हरिजन, मुसलमान और पिछड़ी जातियों के हैं. कांशीराम को कुछ मुसलमानों का समर्थन भी मिलेगा. वी.पी. सिंह कांशीराम द्वारा हरिजन वोट बटोर लेने पर शिकायत नहीं कर सकते. हां, उनके यादव और कुर्मी वोट कटने का भी खतरा है.

कांशीराम का अभियान सभी उम्मीदवारों से अधिक जोरदार है. उनके नीले झंडे हर कहीं फहराते दिखे और पूरे चुनाव क्षेत्र में हर कहीं दीवार पर हाथी का उनका चुनाव चिन्ह बना दिखा. पार्टी का साइकिल जत्था दिन-रात गांवों में घूमता रहता है. 'वोट के साथ नोट' मांगने वाला उनका जत्था हरिजन बस्तियों में जाता है. इन जत्थों को जितने नोट नहीं मिले उससे अधिक सहानुभूति मिली. कांशीराम ने कहा, "पैसा लेना तो सांकेतिक है. अगर एक जमादार मुझे दो रुपए देता है तो उसे यह हिम्मत होगी कि चुनाव के दिन उसका वोट खरीदने आए कांग्रेसी पर चप्पल उठा दे."

पिछले पखवाड़े इलाहाबाद में उन्होंने अपना चुनाव प्रचार बहुत उग्र लहजे में किया और इससे भिंडरांवाले या घीसिंग के जुबान की बू आ रही थी. अपने समर्थकों से उन्होंने बार-बार कहा, "हम इस सरकार और इन शासक जातियों से पूछते हैं कि वे हमारे अधिकार वोट से देंगे या बुलेट से. अगर वे बुलेट से ही अधिकार देंगे तो हम उसके लिए भी तैयार हैं." जातीय हिंसा को उकसाने के आरोप का उन पर कोई असर नहीं होता. वे कहते हैं, "मैं अपने लोगों से हमले करने के लिए नहीं कह रहा हूं. लेकिन जब जातीय हिंसा फूटेगी तो अचार और चटनी कौन बनेगा? गांव में 100 घर वाले या दो घर वाले?" अपने समर्थकों के लिए वे भीमराव आंबेडकर के अवतार हैं तो अपने आलोचकों के लिए फासीवादी जातिवादी.

फासीवादी कहने पर कांशीराम की प्रतिक्रिया बहुत हिंसक हो सकती है लेकिन सेना और सैनिकवाद के प्रति अपनी दीवानगी को वे छिपाते भी नहीं. बहुजन समाज पार्टी का यह उम्मीदवार पंजाब के रोपड़ जिले के खवासपुर गांव के एक सैनिक परिवार का बेटा है. उनका कहना है कि उनके परिवार के आठ लोग प्रथम विश्व युद्ध में और दो दूसरे विश्व युद्ध में लड़े थे. उनके दो चचेरे भाई पैरा कमांडो थे जिनमें से एक ऑपरेशन ब्लू स्टार में मारा गया. वे खुद भी रक्षा मंत्रालय के पुणे स्थित विस्फोटक अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला में सात साल तक काम कर चुके हैं. यहां आंबेडकर समर्थकों के प्रभाव में उन्होंने विस्फोटकों के अध्ययन से जुड़ी अपनी पीएचडी पूरी करने की योजना छोड़ दी और जाति की विस्फोटक राजनीति शुरू की. अपनी इसी पृष्ठभूमि के कारण वे इलाहाबाद में अपने चुनाव अभियान का संचालन भी सेना वाले अंदाज में कर रहे हैं. उनकी पार्टी के लिए यह अब तक का सबसे अहम चुनाव है. उनकी पार्टी ने होटल ताउसी के छह कमरों की एक पूरी मंजिल किराये पर ले रखा है. यहीं कंट्रोल रूम है जहां से आदेश

चुनाव सभाओं में बीरबहादुर मंच पर आगे ही बैठते और तबादले, प्रोन्नति और कर्ज की मांग की अर्जियों पर दनादन दस्तखत करते दिखे

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उनके समर्थक जंग बहादुर पटेल के घर में बने संपर्क कक्ष को भेजे जाते हैं. पूरे चुनाव क्षेत्र को पांच भागों में बांट दिया गया है और हर भाग के पास अपनी गाड़ियां हैं, अपने भंडार हैं, अपनी सामूहिक रसोई है.

अधिकांश काम सात जत्थों में बांट दिया गया है. इनमें हाथी के 50,000 नीले निशान बनाने वालों का पेंटिंग जत्था, साइकिल जत्था, भिक्षाटन जत्था, जन जागरण जत्था, भाषणकर्ताओं का जत्था और खुफिया जत्था भी है. कांशीराम बताते हैं कि खुफिया जत्थे में 500 लोग हैं. इनमें अधिकांश गुप्तचर ब्यूरो और रॉ के अवकाशप्राप्त कर्मचारी हैं और वे विपक्षी खेमे की रणनीति का पता करते हैं. हर जत्थे के लोगों का काम एकदम अनुशासित तरीके से चलता है. उनकी निष्ठा और लगन देखकर ही बाहरी लोगों को कांशीराम की ताकत का एहसास होता है.

लेकिन इस दिलचस्प 'सैनिक मुहिम' के पीछे एक बहुत ही चालाक और कठोर दिमाग काम करता है जो जातिगत भावनाओं को भुनाने में माहिर है. वर्षों की मेहनत से कांशीराम ने नौकरशाहों के बीच अपना गुप्त समर्थक वर्ग विकसित कर लिया है. यही लोग उनकी मुहिम की रीढ़ हैं. उनके पैसे तथा समर्थन पर ही उनकी पार्टी टिकी है. कांशीराम द्वारा छापे गए 'करेंसी' नोटों को यादगार समझकर वे अपने पास रख लेते हैं और असली पैसा दे देते हैं.

ऐश महल में बनते बैनर; और चुनाव चिन्ह बने बच्चे के साथ वी.पी. सिंह

कांशीराम का दावा है कि वे अपार धन जुटा सकते हैं. इलाहाबाद उनके लिए भी अग्निपरीक्षा ही है. यहां सफल होने के बाद ही वे इंका के विशाल वोट बैंक में सेंध लगा सकेंगे. इसीलिए उन्होंने खुद मैदान में उतरने का फैसला किया. उन्होंने कहा, "चाहे वी.पी. सिंह जैसे अच्छे नेता को हराना ही क्यों न पड़े, मुझे चुनाव मैदान में उतरना ही था. सिंह हारें यह अच्छा तो नहीं लगेगा लेकिन माफ कीजिए, मैं कुछ कर नहीं सकता."

कांशीराम कौन हैं, इस बात को लेकर भी इलाहाबाद में कम तरह के चर्चे नहीं हुए. कोई उन्हें हरिजन लड़की से शादी करने वाला ब्राह्मण बताता है तो कोई ईसाई. और इस तरह के चर्चों को कांग्रेसी लोगों ने और हवा दी. खुद मुख्यमंत्री वीरबहादुर सिंह ने कहा कि वे आखिर में रोज एक 'भंडाफोड़' करके कांशीराम की असलियत को सामने ले आएंगे. अखबारों-पत्रिकाओं ने भी इस बेकार मुद्दे को खूब उछाला और बाद में कांशीराम ने खुद सारी बातें स्पष्ट कीं.

धूमधाम से होने वाले इस उपचुनाव में मुकाबला तिकोना ही है, पर अमिताभ के चुनाव मैदान में उतरने की उम्मीद से 65 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में आ गए. इनमें तीन तो दक्षिणी राज्यों से आए और नामांकन पत्र भरने के बाद से उन्हें दोबारा नहीं देखा गया. एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं, भगवाधारी गुलाब शंकर उर्फ बमबम बाबा और दूसरे हैं कोई उर्फ 'मृतक', क्योंकि गलती से कभी सरकारी दस्तावेजों में उन्हें मृत बता दिया गया था. इन निर्दलीय उम्मीदवारों की कोई निजी हैसियत भी नहीं है. लेकिन उनके एक साथ जुटने से एक समस्या पैदा हो गई है. मतपत्र 75 सेंमी लंबा हो गया है जो अब तक का सबसे बड़ा मतपत्र है. अनाज ओसाते किसान का नया चुनाव चिन्ह पाने वाले वी.पी. सिंह के लिए यह अधिक कष्टकारी है. एक निर्दलीय उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह हल चलाता किसान है और उससे उलझन होती है. वी.पी. सिंह समर्थक इस बात से इतने परेशान थे कि उन्होंने 40 लोगों और बच्चों का ऐसा जत्था बनाया जो चुनाव चिन्ह जैसी मुद्रा में ही घूमते रहे. लगता है कि इस चुनाव चिन्ह के कारण ही वी.पी. सिंह कुछ मतों से वंचित रह जाएंगे.

बहरहाल, ऐसे चंद वोटों से वी.पी. सिंह के चुनावी भविष्य पर बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है. 'विजेता' के रूप में उभरने के लिए उन्हें सिर्फ जीत की नहीं, वोटों के विशाल अंतर से जीत की जरूरत है. अजीत सिंह ने एक समय कहा था, "अगर वे महज कुछ हजार वोटों से जीते तो बहुत अच्छा नहीं होगा."

इस उपचुनाव को खुद जनमत संग्रह में बदलकर वी.पी. सिंह फंस-से गए हैं. कम वोटों से जीत उनकी करीब-करीब हार ही मानी जाएगी. और हार तो विनाशकारी ही होगी. देश के उपचुनावों के इतिहास के इस सबसे महत्वपूर्ण चुनाव का सारा दारोमदार बस इसी तथ्य पर टिका है.

—शेखर गुप्ता और दिलीप अवस्थी, इलाहाबाद में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उपचुनाव

फीके पड़े इंका के तेवर

एकता के अद्भुत प्रदर्शन से विपक्ष का पलड़ा भारी

यह विपक्षी एकता का अद्भुत प्रदर्शन था. हिंदी प्रदेशों के अलावा गुजरात, जम्मू-कश्मीर और पश्चिम बंगाल में उपचुनावों की एकमात्र खासियत यह रही कि विपक्ष ने प्रत्याशियों के चयन और चुनाव अभियान में अप्रत्याशित समझदारी दिखाई. एकता का प्रदर्शन इतना जोरदार था कि अनेक दिग्गज राजनीतिक भी साझा उम्मीदवारों के पक्ष में मैदान से हट गए. उत्तर प्रदेश के छपरौली में लोकदल का प्रत्याशी जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में बैठ गया और उधर जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में भाजपा का उम्मीदवार विपक्ष के साझा प्रत्याशी पैंथर्स पार्टी के भीम सिंह के पक्ष में मैदान से हट गया.

छपरौली, हरियाणा में सिरसा और फरीदाबाद, राजस्थान में पाली, गुजरात में गोधरा, मध्य प्रदेश में खरसिया और पश्चिम बंगाल में बड़बानी के करीब एक करोड़ मतदाताओं ने बोफोर्स और एचडीडब्ल्यू पनडुब्बी के बारे में शायद सुना भी न हो पर हर जगह राजीव सरकार के भ्रष्टाचार का मुद्दा गूंजने लगा. देवीलाल के अनुसार यह निश्चय ही अगले आम चुनाव की रिहर्सल थी.

हालांकि ये उपचुनाव राजीव सरकार के बारे में जनमतसंग्रह नहीं बने, फिर भी उनका महत्व इसलिए है कि इंका अपने ही गढ़ों को बचाने में लगी थी. लोकसभा की सभी सात सीटें और विधानसभा की 11 में से पांच सीटें इंका का गढ़ मानी जाती रही हैं. इनके ध्वस्त होने से सत्ता पार्टी के लिए बड़ा राजनैतिक संकट खड़ा हो सकता है.

इन उपचुनावों में इंका के तीन मुख्यमंत्रियों—बीरबहादुर सिंह, शिवचरण माथुर और अर्जुन सिंह—की राजनैतिक किस्मत भी दांव पर लग गई

इन चुनावों में न सिर्फ सत्तारूढ़ पार्टी का भाग्य बल्कि महत्वपूर्ण हिंदी क्षेत्र में इंका के तीन मुख्यमंत्रियों—बीरबहादुर सिंह (उत्तर प्रदेश), अर्जुन सिंह (मध्य प्रदेश) और शिवचरण माथुर (राजस्थान)—का राजनैतिक भविष्य भी दांव पर लग गया. उधर हरियाणा के कुछ घमासानों में मुख्यमंत्री देवीलाल के लिए अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगी खुर्शीद अहमद को फरीदाबाद लोकसभा हलके से जिताना प्रतिष्ठा का मुद्दा बन गया.

हरियाणा के सिरसा (मतदाता—8.82 लाख) में इंका ने 25 वर्षीया शैलजा कुमारी को मैदान में उतारा. लोकसभा की यह सीट उनके पिता दलबीर सिंह की मृत्यु से खाली हुई थी. दरबाकलां गांव में शैलजा के प्रचार का मुद्दा लोगों को यह याद दिलाना था कि वे इसी क्षेत्र की 'बेटी' हैं. उन्होंने मतदाताओं को यह भी याद दिलाया कि बतौर सांसद उनके पिता के तीन कार्यकालों के दौरान ही इस क्षेत्र का विकास हुआ.

लेकिन क्षेत्र की 'बेटी' के भरपूर प्रयास के बावजूद लहर उनके प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार

छपरौली में चुनाव प्रचार करते अजीत सिंह: प्रतिष्ठा दांव पर

प्रमोद पुष्करणा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लोकदल के हेतराम के पक्ष में बहती दिखी. हेतराम ने नामजदगी का पर्चा दाखिल करने से पांच दिन पहले बैंक मैनेजर के पद से इस्तीफा दिया था. पिछले साल हरियाणा विधानसभा के चुनाव में सिरसा क्षेत्र से लोकदल के सात विधायक चुने गए थे और बाकी दो सीटों पर भाजपा और माकपा के उम्मीदवार जीते थे.

यहां चुनाव प्रचार के मुख्य मुद्दों में केंद्र में भ्रष्टाचार के अलावा दोनों उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता भी मुद्दा रही. इंका ने इस बात को उछाला कि शैलजा दिल्ली कान्वेंट ऑफ जीसस ऐंड मेरी में पढ़ी हैं और वे अंग्रेजी साहित्य में एमए और एमफिल हैं. पर हेतराम भी पीछे नहीं थे. उनके पास तो अपनी एमए की दो डिग्रियां थीं.

देश की राजधानी से सटे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में चुनाव कुछ अधिक ठोस मुद्दे पर लड़ा गया. लोकदल के उम्मीदवार खुर्शीद अहमद ने हरियाणा में सरकार बनने के बाद किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा उछाला. नूह गांव की एक सभा में उन्होंने कहा, "राज्य सरकार के दायरे में आने वाले सभी कर्जों को हमने माफ कर दिया है. बाकी कर्जे राष्ट्रीयकृत बैंकों ने दिए थे जो अभी केंद्र और राजीव गांधी के आदेश पर चलते हैं. इसलिए आप हमें वोट दीजिए ताकि केंद्र में पहुंचकर हम इन बैंकों द्वारा दिए गए कर्जे भी माफ कर सकें." देवीलाल की बेहद लोकप्रियता को भुनाते हुए उन्होंने कहा, "देवीलाल ने राजीव गांधी का विकल्प विश्वनाथ प्रताप सिंह के रूप में तलाशा है. विश्वनाथ जी प्रधानमंत्री बनकर देवीलाल की नीतियों को लागू करेंगे."

लेकिन चुनाव में धार्मिक रंग भी चढ़ने लगा. कुल 8.69 लाख मतदाताओं में से करीब 2.3 लाख मेव मुसलमान हैं और खुर्शीद उनके एक नेता हैं. मेव बिरादरी के ही दो अन्य नेता तैयब हुसैन और सरदार खां हाल ही में इंका छोड़कर लोकदल में जा मिले थे. अखेड़ा गांव के सरपंच अयूब खां ने कहा, "देवीलाल हों या नहीं, मेव बिरादरी के सभी वोट एकमुश्त खुर्शीद के बक्से में पड़ेंगे."

इंका उम्मीदवार जे.पी. नागर राजनीति में नौसिखुए हैं. उम्मीदवारी तो उन्हें इंका महासचिव गुलाम नबी आजाद की मेहरबानी से मिली. विपक्ष की कड़ी चुनौती का सामना करने के लिए इंका ने सांप्रदायिक भावना भड़काने की खतरनाक रणनीति अख्तियार की. उसने लोकदल के मुसलमान उम्मीदवार के खिलाफ नागर को एकमात्र हिंदू उम्मीदवार के रूप में पेश किया.

उधर राजस्थान में लोकसभा के पाली और विधानसभा के खेतड़ी चुनाव क्षेत्र मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर की ताकत की परीक्षा बन गए. वे अपदस्थ मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी के समर्थकों से पहले ही परेशान हैं. जोशी समर्थकों ने चुनाव अभियान में बड़े बेमन से हिस्सा लिया. हालांकि पाली में इंका उम्मीदवार शंकरलाल राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं पर पार्टी के असंतुष्टों ने उनकी भी हालत खराब कर दी.

माथुर के लिए बदतर स्थिति तो यह रही कि राज्य लगातार सूखे की मार से झुलसता रहा और सरकारी राहत कार्य कहीं ही देखने को मिलते थे. भाजपा के चतुर नेताओं ने इसी मुद्दे को उछाला. इसके अलावा पाली से भाजपा उम्मीदवार गुमानमल लोढा भैरोंसिंह शेखावत और विजयराजे सिंधिया सरीखे पार्टी नेताओं के पुराने विश्वासपात्र हैं.

खेतड़ी विधानसभा हलके में इंका के डॉ. जितेंद्र का भाजपा के हजारी गूजर और लोकदल के प्रद्युम्न सिंह से त्रिपक्षीय मुकाबला रहा. उसने 1984 के उस चर्चित गोलीकांड

नामजदगी का पर्चा भरने जाते अर्जुन सिंह: भीतरी विरोध का सामना

विनय शर्मा

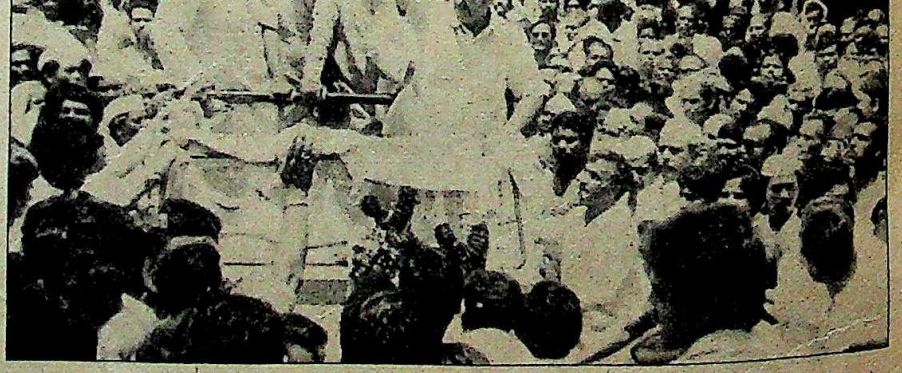

की यादें फिर ताजा कर दीं जिसमें पुलिस ने डीग के निर्दलीय जाट विधायक मान सिंह की हत्या कर दी थी. माथुर के खिलाफ साझी लड़ाई में मान सिंह के परिवार से सहयोग लेने वाले भाजपा नेता शेखावत ने कहा, "यह सरकार भ्रष्ट है. हमें पूरा यकीन है कि अगले आम चुनाव में जनता इसे उखाड़ फेकेगी."

इंका में अंदरूनी झगड़ों के कारण मध्य प्रदेश के खरसिया विधानसभा क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के लिए मुश्किलें खड़ी हुईं. उन्हें न सिर्फ विपक्ष के साझा उम्मीदवार और भाजपा के ताकतवर नेता दिलीप सिंह जूदेव का सामना करना था बल्कि अपनी ही पार्टी के कुछ लोगों खासकर पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा और केंद्रीय रेलमंत्री माधवराव सिंधिया द्वारा उनके खिलाफ चलाए जा रहे जोरदार अभियान से भी जूझना पड़ गया.

लेकिन अर्जुन सिंह के लिए उम्मीद की एकमात्र किरण यह थी कि खरसिया हमेशा से इंका का गढ़ रहा है जो 1977 की जनता आंधी में भी टिका रहा. 1980 और 1985 में भी इंका ने कमोबेश बढ़त बनाए रखी. फिर भी पार्टी में व्याप्त असंतोष और विपक्ष के साझे मोर्चे के मद्देनजर अर्जुन सिंह को नाकों चने चबाने पड़े. हालांकि विपक्षी दलों के मुकाबले इंका का प्रचार काफी फीका रहा पर अर्जुन सिंह के समर्थक बिलकुल आश्वस्त थे क्योंकि उनका मानना था कि आदिवासी-बहुल उस इलाके के लोग मुख्यमंत्री द्वारा पिछड़े समुदायों के लिए चलाई गई अनेक कल्याण योजनाओं की पूरी जानकारी रखते हैं.

इसके बावजूद जूदेव कहीं पीछे नहीं रहे हैं. आदिवासियों के बीच सामाजिक सेवाओं के माध्यम से उन्होंने अपना आधार बना रखा है. अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी सरीखे पार्टी दिग्गजों तथा बनारसी दास गुप्त (लोकदल) और सूरजभान (भाजपा) जैसी हरियाणा की प्रमुख हस्तियों की मौजूदगी से उनके प्रचार में खासी तेजी रही. उधर अर्जुन सिंह के प्रचार में कई वरिष्ठ इंका नेता नदारद रहे.

इसीलिए अर्जुन सिंह ने कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया. उनके समर्थकों को पता था कि यदि जीत का फासला पिछले चुनावों से

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कम रहा तो इसमें मुख्यमंत्री की तामझाम वाली छवि पर खासा असर पड़ेगा.

खरसिया में जहां अर्जुन सिंह का अस्तित्व दांव पर लगा था तो वहीं छपरौली में जनता पार्टी के नए अध्यक्ष अजीत सिंह की प्रतिष्ठा का इम्तहान था. जाटबहुल यह हलका उनके दिवंगत पिता चरण सिंह और बहन डॉ. सरोज वर्मा का क्षेत्र रहा है. यहां जनता उम्मीदवार नरेंद्र सिंह और इंका के रामपाल के बीच सीधा मुकाबला है.

जनता अध्यक्ष इस क्षेत्र के तूफानी दौरे पर रहे. तीन दिन में ही उन्होंने घर-घर जाकर छपरौली के 1.59 लाख में से आधे मतदाताओं से संपर्क कायम किया. इसके अलावा 40 जनसभाओं को भी उन्होंने संबोधित किया. अजीत सिंह को अगले प्रधानमंत्री के रूप में पेश कर रहे उनके समर्थकों का कहना था कि उनका लक्ष्य तो दरअसल जीत का भारी अंतर पैदा करना है. एक जनता विधायक ने कहा, "पिछली दफा मोरारजी देसाई चौधरी साहब (चरण सिंह) पर बाजी मार ले गए थे. अब अजीत सिंह उन्हीं मोरारजी की पार्टी के अध्यक्ष हैं."

यहां भ्रष्टाचार और सत्ताधारी दल द्वारा

विपक्ष दलों ने इन उपचुनावों में भ्रष्टाचार के मुद्दे को जिस प्रभावशाली तरीके से उछाला उसके कारण कांग्रेस को बचाव की मुद्रा अपनानी पड़ गई

ली गई 'दलाली' जैसे विपक्ष के आकर्षक नारों का ही बोलबाला रहा. इंका बचाव की मुद्रा में रही. युवा इंका नेता एस. खौक्कड़ ने एक बैठक में गुलाम नबी आजाद को बताया, "हमें यह सीट जीतने की कोई आशा नहीं है. हमारी कोशिश बस इतनी है कि उनकी जीत का फासला कम से कम रहे जिससे अगले लोकसभा चुनाव में अजीत सिंह यहां से खड़े हों तो उन्हें कड़े मुकाबले का सामना हो."

गुजरात के तीन उपचुनावों पर जातिवाद की छाया बनी रही. सौराष्ट्र के द्वारका और मलीया दो विधानसभा क्षेत्रों और पिछड़े जिले पंचमहल के गोधरा लोकसभा क्षेत्र में चुनाव का घमासान हुआ. तीनों क्षेत्रों में भाजपा और जनता पार्टी का एक-एक साझा उम्मीदवार था.

लेकिन सारी नजरें गोधरा पर ही लगी रहीं. दिवंगत पीलू मोदी 60 वाले दशक के अंत और 70 वाले दशक के शुरू में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे. पर पिछले तीन चुनावों में इंका उम्मीदवार यहां से जीतता आ रहा है. इंका ने यहां क्षत्रिय जाति के विधायक उदय सिंह बारिया को जनता पार्टी के विधायक शांति पटेल के खिलाफ भिड़ा दिया. इस क्षेत्र के 50 फीसदी से अधिक

(ऊपर से नीचे) पैंथर पार्टी के भीम सिंह, इंका की शैलजा कुमारी और भाजपा के दिलीप सिंह जूदेव: कांटे की टक्कर

प्रशांत पंजियार

प्रमोद पुष्करणा

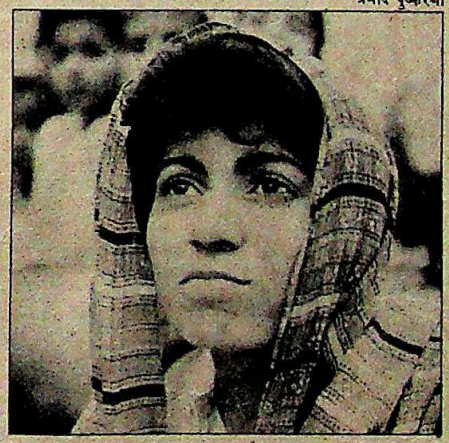

मतदाता क्षत्रिय जाति के ही हैं.

पर चुनाव अभियान में कोई महत्वपूर्ण मुद्दे नहीं उठाए गए. इंका नेता ज्यादातर पंजाब और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे घिसे-पिटे मुद्दों को ही उछालते रहे. सत्ताधारी दल का नारा था, "राजीव ही देश को नेतृत्व देने में सक्षम है." इसके विपरीत जनता पार्टी के अभियान की कमान पूर्व मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल के हाथ में रही और उन्होंने सरकार में भ्रष्टाचार और बोफोर्स जैसे मुद्दों को उभारा.

उत्तरी राज्य जम्मू-कश्मीर के उधमपुर लोकसभा चुनाव में विपक्ष के साझा उम्मीदवार और पैंथर्स पार्टी के भीम सिंह अपने इंका प्रतिद्वंद्वी मुहम्मद अयूब खां से सीधे मुकाबले में भिड़े. 1984 के चुनाव में भीम सिंह इंका के गिरधारी लाल डोगरा से एक लाख से अधिक मतों से हार गए थे.

इस बार इस हिंदूबहुल क्षेत्र में जातीय गणित भीम सिंह के पक्ष में दिखा. उधमपुर के कुल सात लाख में से मुसलमान मतदाताओं की संख्या 1.5 लाख है. हरिजन 18 फीसदी हैं और वे परंपरागत रूप से इंका के समर्थक रहे हैं. लेकिन क्षेत्र के चार लाख हिंदू मतदाताओं में उनकी अपनी राजपूत जाति के 70 फीसदी मतदाता हैं.

जम्मू-कश्मीर में भ्रष्टाचार और सत्ताधारी गठजोड़ द्वारा चुनावी वायदों का पूरा न किया जाना ही मुख्य मुद्दे रहे. इनकी बौछार होते ही इंका को बचाव में आना पड़ा. जवाब में वह माधवराव सिंधिया को भेजकर राजपूत मतदाताओं को फुसलाने की कोशिश भर ही कर सकी.

पूर्व में लोगों की नजरें पश्चिम बंगाल के बड़बानी और कुमारग्राम के दो विधानसभा क्षेत्रों पर लगी रहीं. यहां इंका ने चुनाव प्रचार तो बड़े धूम-धड़ाके के साथ शुरू किया पर वह अधिक देर नहीं टिक पाई. राज्य इंका अध्यक्ष प्रियरंजन दासमुंशी और पार्टी के महासचिव ऑस्कर फर्नांडीस ने बड़बानी में बड़ी-बड़ी सभाओं को संबोधित किया. लेकिन इसके तुरंत बाद दासमुंशी सुनील शास्त्री के प्रचार में इलाहाबाद चले गए. इंका के मुकाबले माकपा और क्रांतिकारी समाजवादी दल की चुनावी भिड़ंत वाले इन दोनों क्षेत्रों में वाममोर्चा ने केंद्र द्वारा पश्चिम बंगाल की उपेक्षा को ही मुख्य मुद्दा बनाया.

देश भर में चुनाव अभियान के दौरान एक ही बात साफ तौर पर उभरी और वह यह कि विपक्ष ने भ्रष्टाचार जैसे राष्ट्रीय मुद्दे को जन-जन तक पहुंचाकर इंका को बचाव की मुद्रा में ला खड़ा किया.

—पंकज पचौरी, उदय माहूरकर, कमलजीत रतन और ब्यूरो रिपोर्ट

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कर्नाटक

असंतोष की तीखी आंच

पार्टी की अंदरूनी कलह से हेगड़े सरकार टूट के कगार पर

मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े आसमान से गिरे तो खजूर पर अटक गए. 1983 में उन्हें कांग्रेस के हमलों से अपनी अल्पमत सरकार को बचाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा था. आज वे फिर लगभग वैसी ही स्थिति में हैं. 1985 के चुनाव में भारी जीत के बावजूद आज पार्टी में अंदरूनी विद्रोह के कारण उनकी सरकार वस्तुतः अल्पमत में आ गई है और हेगड़े इसकी रास मजबूती से थामे रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. पार्टी के भीतर यह विद्रोह करवाया है पूर्व लोक निर्माण मंत्री एच. देवगौडा ने.

इससे पहले हेगड़े सरकार इस तरह टूट जाने के कगार तक कभी नहीं पहुंची थी. मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग के स्वर पिछले पखवाड़े अपने चरम पर पहुंच गए. राज्य के इंका प्रमुख जनार्दन पुजारी कहते हैं, "225 सदस्यों वाली विधानसभा में हेगड़े समर्थक विधायकों की संख्या घटकर 89 रह गई है. लिहाजा मुख्यमंत्री को अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया है."

विधान परिषद के लिए 6 जून को हुए द्विवार्षिक चुनावों के दौरान ही यह स्पष्ट हो गया कि हेगड़े अल्पमत सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं. जनता पार्टी के जहां छह अधिकृत उम्मीदवार चुने गए, वहीं हेगड़े के कट्टर दुश्मन देवगौडा के दो बागी उम्मीदवार—के.बी. पिलप्पा और एम. विवेकानंदैया—भी विजयी हुए. तीसरे बागी उम्मीदवार वी.एस. उग्रप्पा भी सिर्फ एक वोट से हार गए.

जनता पार्टी के 139 में से 50 विधायकों ने देवगौडा के उम्मीदवारों को वोट दिया. यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है. असंतुष्ट गुट के सदस्यों की संख्या अब 47 से आगे निकल चुकी है यानी वे विधानसभा में अलग बैठ सकते हैं. उन्हें दलबदल विरोधी कानून के तहत दंडित भी नहीं किया जा सकता. उधर इंका के सभी तीनों उम्मीदवार विजयी हुए. मुख्यमंत्री के लिए ज्यादा परेशानी की बात यह रही कि उनके कट्टर विरोधी इंका उम्मीदवार ए.के. सुब्बैया को सभी उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा वोट मिले.

पार्टी में चल रही उठा-पटक में देवगौडा इस बार ऊपर ही नजर आए. महीनों तक सख्त चेहरा ढोते रहे इस बागी नेता ने चहकते हुए कहा, "यह हमारी नैतिक जीत है." दूसरी तरफ हेगड़े ने तर्क दिया, "पिछली 3 मई को ही बात साफ हो गई थी कि मुझे अपनी पार्टी के विधायकों का समर्थन हासिल नहीं है. वही स्थिति अब भी है."

जनता पार्टी असंतोष और अनुशासनहीनता के दुष्चक्र में इस कदर फंस चुकी है कि उसके भीतर टकराव बढ़ता ही जा रहा है और लगभग हर महीने शक्ति परीक्षण हो रहा है. हेगड़े ने शिकायत की, "मुझे परेशान करने के लिए असंतुष्ट सदस्य चुनाव जैसे अहम मौकों पर ही हमेशा दबाव डालते हैं."

इस बार भी असंतुष्टों ने मौके का लाभ उठाया. पार्टी को जान-बूझकर तोड़ने के कगार तक ले जाने वाले देवगौडा ने विधान परिषद चुनाव से विद्रोही उम्मीदवारों के नाम वापस लेने से इनकार कर दिया. उनकी मांग थी कि प्रदेश जपा अध्यक्ष पद से एम.पी. प्रकाश को हटाकर पूर्व पशुपालनमंत्री सिद्धरमैया को

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बैठाया जाए, तभी वे असंतुष्ट उम्मीदवारों के नाम वापस लेंगे. असंतुष्ट नेता यह बदलाव क्यों चाहते थे, इसके बारे में हेगड़े के एक वफादार कहते हैं, "देवगौडा पार्टी मशीनरी पर कब्जा करना चाहते हैं क्योंकि आगामी चुनाव सिर्फ 18 महीने दूर रह गया है."

लेकिन लगातार चलने वाले इन झगड़ों के कारण जनता पार्टी के दोनों ही धड़ों को नुकसान पहुंच सकता है. इस अंदरूनी कलह ने राष्ट्रीय स्तर पर तो विपक्ष की साख को ठेस पहुंचाई ही है. विडंबना यह है कि जब विपक्ष के नेता विजयवाड़ा में एकता के लिए इकट्ठे हुए थे तो उधर जनता पार्टी की कर्नाटक इकाई भारी संकट में थी.

28 मई को एम.एस. नारायणराव की अगुआई में चार प्रमुख असंतुष्ट विजयवाड़ा के गणवरम हवाई अड्डे पर पार्टी अध्यक्ष अजीत सिंह, मधु दंडवते, बीजू पटनायक और रामनरेश यादव जैसे नेताओं से मिलने पहुंचे और इस मामले में हस्तक्षेप करने को कहा. देवगौडा की ओर से अजीत सिंह को दिए एक पत्र में सिद्धरमैया को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर 'संकट टालने' का आग्रह किया गया था. लेकिन हेगड़े ने इनकार करते हुए कहा, "ऐसे दबावों और धौंस-धमकियों के आगे मैं झुकने वाला नहीं." हेगड़े के इस जवाब से देवगौडा भड़क उठे और उन्होंने अपनी जाति—वोक्कलिगा—बहुल क्षेत्रों का दौरा शुरू कर दिया. जनसभाओं में उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से कहा कि यदि उन्हें ज्यादा परेशान किया गया तो वे पार्टी को तोड़ देंगे.

इस कलह का कोई अंत होता नहीं दिखता. यानी लगता है कि जब-जब देवगौड़ा को अवसर मिलेगा, वे हेगड़े पर आक्षेप करने से नहीं चूकेंगे. बंगलूर जाकर सुलह कराने में विफल रहे दंडवते ने भी माना कि देवगौडा ने परिषद की 24 सीटों के लिए 3 जुलाई को होने वाले चुनावों (जिसमें स्वायत्त संस्थाओं के प्रतिनिधि भी वोट देंगे) या उसके बाद पार्टी संगठन के चुनावों में किसी किस्म का सहयोग करने का आश्वासन नहीं दिया है.

देवगौडा को पक्का विश्वास हो गया है कि हेगड़े पर दबाव बनाए रखने लायक ताकत अब उनमें है. लेकिन हकीकत यह है कि खुद देवगौडा भी पाक-साफ नहीं हैं. गुप्तचरों के दस्तों (सीओडी) और लोक आयुक्त की रिपोर्टों के अनुसार उन पर भाई-भतीजावाद, पद के दुरुपयोग और मैसूर नगर विकास ट्रस्ट (सीआईटीबी) के माध्यम से अपने संबंधियों को प्लॉट आवंटित करने में पक्षपात करने के आरोप हैं. लोक आयुक्त की रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि अपनी एक करीबी रिश्तेदार सावित्रिम्मा को प्लॉट दिलाने के मामले में उन पर जाहिरा तौर पर मामला बनता है. जबकि सीओडी की रिपोर्ट में लिखा है कि "देवगौडा के बेटे रेवन्ना और उनके भाई बालकृष्ण गौडा द्वारा कुछ बेनामी आवेदन तैयार किए गए. ऐसे भी प्रमाण मिले हैं कि आवंटन में कीमतों में हेरफेर की गई और पिछली तारीख से आवंटन किया गया."

पार्कों और खुली जगहों के लिए आरक्षित स्थानों को भी गृह निर्माण के लिए आवंटित किया गया. सीआईटीबी में जातीय आधार पर नियुक्तियां करने के आरोप पर सीओडी की रिपोर्ट का कहना है कि 1983 से 1986 तक जिन इंजीनियरों ने इस प्रतिष्ठान में काम किया, उनमें से 32 में 18 वोक्कलिगा जाति के थे. लेकिन इन आरोपों के बावजूद हेगड़े देवगौडा के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे इसकी संभावना कम ही है. उनके सामने दूसरे विकल्प हैं. वे विधान-सभा को भंग कर सकते हैं या जनता विधायक दल को नया नेता चुनने के लिए कह सकते हैं.

जनता पार्टी में विद्रोह इससे ज्यादा बुरे मौके पर नहीं हो सकता था. देश भर में होने वाले उपचुनावों के दौरान जबकि सभी विपक्षी दल एकता का प्रदर्शन कर रहे हैं, कर्नाटक में जनता पार्टी टूटन के कगार पर खड़ी है. खुद हेगड़े भी मानते हैं, "राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जनता पार्टी के भीतर विभाजन लोगों में इसकी छवि खराब कर रहा है. लोग पूछते हैं कि जब हम आपस में ही मिल कर नहीं रह सकते तो राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की एकता कैसे कायम रखेंगे."

और यही सवाल इंका भी उठा रही है. इंका नेता वीरप्पा मोइली ने कहा, "जब वे अपने टुच्चे अंदरूनी झगड़े नहीं निबटा सकते तो उनसे इंका का विकल्प बनने की उम्मीद कैसे की जा सकती है?" हेगड़े भी मानते हैं, "हमने इंका को अपने खिलाफ प्रचार के लिए काफी मसाला जुटा दिया है." लेकिन दंडवते को इसका शायद ज्यादा खेद नहीं है, "इंका हम पर कैसे कीचड़ उछाल सकती है, जबकि उसकी अपनी इलाहाबाद इकाई अमिताभ बच्चन और सुनील शास्त्री के खेमों में बंटी हुई है."

लेकिन सचाई यह है कि कर्नाटक की जनता सरकार में आए दिन के झगड़ों के कारण मध्यम वर्ग का सरकार से मोहभंग हो गया है. पुजारी व्यंग्य करते हैं, "कर्नाटक की कलह से यह साबित हो गया है कि सरकार चलाना विपक्षी दलों के बस की बात नहीं." जनता पार्टी के असंतुष्टों के प्रवक्ता एम.एस. नारायणराव का कहना है, "सिर्फ राजीव गांधी को हटाने के लिए विपक्षी एकता के केंद्रीय प्रयासों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है. कोई भी नेता इन सवालों को नहीं उठाता कि यदि वे जीत गए तो उनका आगे का कार्यक्रम क्या होगा."

जनता पार्टी एक बार पहले 1979 में भी यह दौर देख चुकी है. तब भी इसके नेता अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं के लिए आपस में लड़-भिड़ रहे थे. और अब कर्नाटक में जनता सरकार बनाने का बहुप्रचारित प्रयोग भी असफल साबित हो रहा है. अपना पहला कार्यकाल समाप्त होते-होते सरकार विपक्षी गठबंधनों—भाकपा, माकपा और भाजपा—का समर्थन खो बैठी थी. अब दूसरे कार्यकाल के समाप्त होते-होते अंदरूनी कलह ने पार्टी में ही गहरी दरारें डाल दी हैं. और हेगड़े, जिनमें कभी विपक्षी एकता की धुरी बनने की संभावनाएं नजर आती थीं, आज अपने ही सहकर्मियों के कारण परेशान हैं.

—अनीता प्रताप

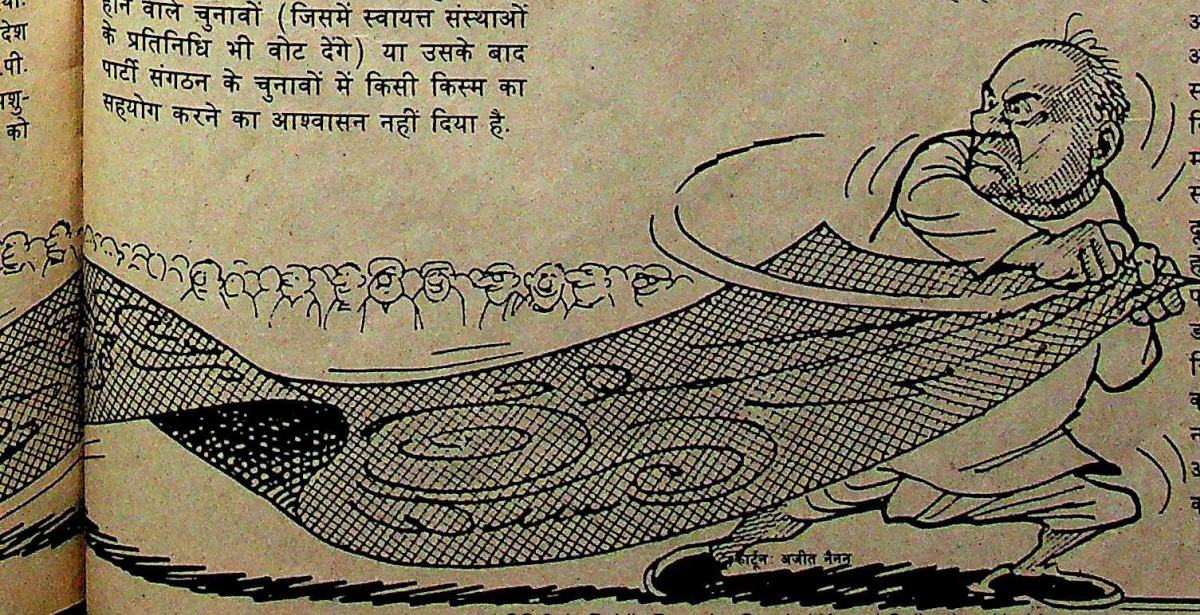

कार्टून: अजीत नैनन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पंजाब

मौका खोने में माहिर

स्वर्णमंदिर के मामले में सरकार अभी अनिर्णय की स्थिति में

नई दिल्ली के नीति निर्धारक पंजाब के बारे में रणनीति को लेकर शायद ही कभी सचमुच आश्वस्त हो पाते हों. लेकिन पिछले पखवाड़े वे ऑपरेशन ब्लैक थंडर की उपलब्धियों का लेखाजोखा कर ही रहे थे कि शिरोमणि गुरद्वारा प्रबंधक समिति ने अकाल तखत के जत्थेदार जसबीर सिंह रोडे और चार दूसरे मुख्यग्रंथियों को बरखास्त करके उन्हें औंधे मुंह गिरा दिया.

शुरू में गुरद्वारा समिति की हालत पतली थी. केंद्र द्वारा दबाव और प्रचार तंत्र का चतुराई से इस्तेमाल करने पर भी सिखों की यह धार्मिक-राजनैतिक संस्था स्वर्ण-मंदिर सौंपे जाने से पहले सरकार की 10 शर्तें मानने में हिचकिचा रही थी. जबकि सरकार इन शर्तों को मानने की लिखित गारंटी चाहती थी. इन शर्तों में मंदिर परिक्रमा में बने कमरों को गिराना, उसके दफ्तरों और सराय परिसर को मुख्य मंदिर परिसर से अलग करने वाली सड़क पर सुरक्षा बलों की गश्त में पूरा सहयोग देना और कार सेवा का सामान ले जाने वाले सभी वाहनों की तलाशी में सहायता करना शामिल हैं. फिर भी गुरद्वारा समिति की कार्यकारिणी को केंद्र की यह मांग माननी पड़ी कि मंदिर को दुबारा आतंक-वादियों की पनाहगाह न बनने देने के लिए वह पूर्व सैनिकों का एक बल गठित करे.

लेकिन अपमान से भुनी बैठी गुरद्वारा समिति ने हरमंदिर साहब से 46 कट्टर आतंकवादियों के आखिरी आत्मसमर्पण के ठीक दो हफ्ते बाद पहल फिर अपने हाथ में ले ली. यह रणनीति चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल में तैयार हुई जहां एकीकृत अकाली अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल, सुखजिंदर सिंह और सुरजन सिंह ठेकेदार नजरबंद हैं. उन्होंने अपने समर्थकों से मिल सकने की ढील का फायदा उठाया. एक वरिष्ठ अकाली नेता ने इस बात की पुष्टि की कि मुख्यग्रंथियों की बरखास्तगी गुरद्वारा समिति के प्रधान गुरचरण सिंह तोहड़ा के दिमाग की उपज है जो दो साल से जोधपुर जेल में बंद हैं. उन्होंने ही इसकी सूचना बुड़ैल जेल में बंद एकीकृत अकाली दल के नेताओं को भिजवाई. जब तक सरकार की नींद टूटती और वह 29 मई को उन्हें चंडीगढ़ की इस जेल से हटाकर दिल्ली की तिहाड़ जेल में भेजती, तब तक काफी देर हो चुकी थी. बाद में बादल को कोयंबतूर और ठेकेदार को तिरूचिरापल्ली की जेलों में भेज दिया गया.

शिरोमणि गुरद्वारा प्रबंधक समिति ने स्वर्णमंदिर की मर्यादा भंग होने की सारी जिम्मेदारी मुख्यग्रंथियों के माथे पर डाल दी और उन्हें तुरंत बरखास्त कर दिया

नई रणनीति के तहत गुरद्वारा समिति ने मंदिर की पवित्रता भंग होने की जिम्मेदारी पांचों मुख्यग्रंथियों के खाते में डाल दी. उन्हें हटाकर एक ऐसी टीम लाई गई जो समिति के ही इशारों पर चलती. अकाल तखत का जत्थेदार एक अनजाने अकाली नेता हरचरण सिंह को मुकर्रर किया गया. दिल्ली में कोयले का धंधा करने वाले और कभी बूटा सिंह के विश्वसनीय रहे हरचरण सिंह की एकमात्र काबलियत यह है कि उनके एकीकृत अकाली दल के नेता बादल से करीबी संबंध हैं. दूसरे चार नए ग्रंथी बलबीर सिंह, मोहन सिंह, प्रीतम सिंह और जागीर सिंह भी उतने ही गुमनाम लोग हैं.

रोडे की बरखास्तगी से सरकार को गहरा धक्का लगा. पंजाब के राज्यपाल सिद्धार्थ शंकर राय केंद्र की आखिरी उम्मीद, रोडे को गुमनामी के अंधकार में धकेले जाने से रोकने के लिए भागे-भागे अमृतसर पहुंचे. ऑपरेशन ब्लैक थंडर के पहले ही जाहिर हो चला था कि रोडे की भूमिका अप्रासंगिक बनाई जा रही है. बहरहाल गुरद्वारा समिति की नौ सदस्यीय कार्यकारिणी पर मान-मनौवल का कोई असर नहीं हुआ. उसने पंजाब पुलिस महानिदेशक कंवरपाल सिंह गिल, सीआरपी महानिरीक्षक (सीमा) चमनलाल और अमृतसर के उपायुक्त सरबजीत सिंह की सुलह-सफाई की अनेक कोशिशों के बावजूद अपना प्रस्ताव वापस लेने से इनकार कर दिया. यहां तक कि गिरफ्तारी की धमकी भी उन्हें अपने फैसले से नहीं डिगा सकी.

प्रशांत पंजियार

दूसरे मुख्यग्रंथियों के साथ रोडे (बीच में)

मान-मनौवल का यह नाटक 31 मई को उस वक्त चरम पर पहुंच गया जब प्रशासन ने कार्यकारिणी के छह सदस्यों का वस्तुतः अपहरण कर लिया. उन्हें गिल के साथ देर रात तक बातचीत के लिए कैनाल रेस्ट हाउस स्थित सीआरपी मुख्यालय ले जाया गया. लेकिन यह कोशिश भी नाकाम रही. बाद में गुरद्वारा समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष माल सिंह घुम्मन ने कहा, "जिला प्रशासन की पूरी कोशिश थी कि कार्यकारिणी पर किसी तरह दबाव डालकर ग्रंथियों की बरखास्तगी रद्द करवा दी जाए." कुछ सदस्यों ने तो यहां तक आरोप लगाया कि उन्हें टेलीफोन पर धमकी दी गई थी कि यदि उन्होंने ग्रंथियों को बरखास्त किया तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा.

मान-मनौवल की सभी कोशिशें नाकाम

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

होने के बाद जो हुआ वह तो और भी हैरतअंगेज था. 31 मई को जिला प्रशासन ने अमृतसर जेल में रोडे के लिए एक प्रेस कांफ्रेंस का बंदोबस्त किया. और रोडे का यह बयान कि "वक्त ही बताएगा कौन गद्दार है और कौन वफादार" जनसंपर्क विभाग में टाइप हुआ और उसी ने इसका वितरण भी किया. रोडे ने दावा किया, "मुझे सरबत खालसा ने नियुक्त किया है. इसलिए गुरद्वारा समिति को मुझे बरखास्त करने का कोई अधिकार नहीं." रोडे ने जहां दिल्ली दरबार को स्वर्णमंदिर की पवित्रता भंग करने के लिए दोषी ठहराया, वहीं वे उन लोगों की आलोचना करने से भी नहीं चूके जिन्होंने मंदिर के कमरों में निर्दोष लोगों को यातनाएं दी थीं. गुरद्वारा समिति के फैसले को चुनौती देने के लिए रोडे अब सरबत खालसा बुलाना चाहते हैं पर उन्हें सरकारी समर्थन शायद ही मिल पाए.

लेकिन जिस तरह से सरकार ने जेल अधीक्षक के कमरे में रोडे की प्रेस कांफ्रेंस का बंदोबस्त किया और उनके बयान को बढ़-चढ़कर प्रचारित किया, उससे उसकी निराशा ही झलकती है. इससे गुरद्वारा समिति को काफी फायदा मिला है. भाजपा के उपाध्यक्ष डॉ. बलदेव प्रकाश आरोप लगाते हैं, "सरकार ने सारे कायदे कानून ताक पर रखकर और सभी नैतिक और कानूनी पहलुओं की अनदेखी करके प्रेस कांफ्रेंस का बंदोबस्त किया." यहां तक कि सरकार की पंजाब नीति का समर्थन करती आ रही भाकपा और माकपा सरीखी पार्टियों ने भी सरकार के इस कदम की आलोचना की. आतंकवाद के खिलाफ केंद्र की लड़ाई के प्रबल समर्थक अकाली दल के वयोवृद्ध नेता जीवन सिंह उमरानंगल ने भी रोडे के बचाव की कोशिशों की आलोचना की.

रोडे की वापसी को निरर्थक मानते हुए राज्यपाल सिद्धार्थ शंकर राय ने घोषणा की कि उनका इरादा सिखों के धार्मिक मामलों में दखल देना नहीं है. लेकिन हकीकत यह है कि ऑपरेशन ब्लैक थंडर से जो फायदा सरकार को हुआ वह उसने गुरद्वारा समिति से दुर्व्यवहार करके और उसके फैसले में दखल देकर एकदम खो दिया. इससे यही जाहिर होता है कि सरकार मौका हाथ लगने के बाद भी उसे खो देती है. —विपुल मुद्गल

स्वर्णमंदिर

काली करतूत

स्वर्णमंदिर परिसर में मंजी साहब, दीवान हाल और लंगर की नई विशाल इमारतों के बीच पिछले चार वर्षों से मिट्टी का एक बड़ा ढेर लगा हुआ है. यह पुराने अकाल तखत के मलबे और पवित्र सरोवर की गाद के जमा होने से बना है. एक पवित्र इमारत और एक पवित्र सरोवर से निकली यह मिट्टी पवित्र मानी गई इसलिए शिरोमणि गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इसे कहीं बाहर नहीं फिंकवाया.

लेकिन विडंबना यह है कि 1984 के बाद से मंदिर पर कब्जा करने वाले आतंकवादियों के लिए पवित्रता कोई मायने नहीं रखती. उनके लिए तो यह ढेर फिरौती न देने वालों या पुलिस के मुखबिरों का शव गाड़ देने की सुविधाजनक जगह बन गई थी. जिसे पवित्र मानकर छोड़ दिया गया था उसे आतंकवादियों ने कब्रगाह बना डाला.

यह डरावनी सचाई ऑपरेशन ब्लैक थंडर के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले आतंकवादियों ने खुद बताई. और जब उस ढेर से एक के बाद एक लाशें निकलनी शुरू हुईं तो उस पवित्र मिट्टी में दबा दी गई आतंकवादियों की करतूतें भी उजागर होने लगीं. आत्महत्या करके मरे कुख्यात आतंकवादी सुरजीत सिंह पेंटा के छोटे भाई हरचरण सिंह के हल्के-से संकेत पर मंदिर की मर्यादा बहाल होने के चार दिन बाद यहां से दो लाशें निकाली गईं. इसके एक दिन बाद भिंडरांवाले टाइगर फोर्स के आतंकवादी बलजीत सिंह ने पुलिस की पूछताछ के समय बताया कि कुछ और लोगों को मार कर वहीं दफना दिया गया. अगले 24 घंटों में छह और लाशें निकलीं. एक को छोड़कर बाकी सभी लाशें एकदम सड़-गल गई थीं और करीब-करीब हड्डियां भर ही शेष बची थीं.

अगले दिन खालिस्तान कमांडो फोर्स के स्वघोषित ले. जनरल मलकियत सिंह अजनाला ने बताया कि मलबे में दो और औरतों की लाशें होने की जानकारी उसे है. 20 पार की इन दोनों औरतों की लाशें भी गल गई थीं और उनकी पहचान नहीं हो पाई. लेकिन उनके कंधे से लटकती कृपाण बताती है कि वे अमृतधारी थीं. उनके महंगे कपड़ों से पता चलता है कि वे समृद्ध घराने की रहने वाली थीं.

मलबे से मिला एक और शव

और दो हफ्ते से भी कम समय तक सीआरपी के एक डीएसपी, एक मजिस्ट्रेट और एक डॉक्टर की मौजूदगी में हुई खुदाई में 22 लाशें निकाली गईं. सभी के शरीर पर दमन के स्पष्ट निशान थे. अनेक लाशों की ठठरी ही बची थी. उनके दोनों पांव अभी भी बंधे थे. एक महिला की खोपड़ी एकदम चूर हो गई थी और एक नौजवान का सिर उसके धड़ से अलग था.

सैकड़ों लोग स्तब्ध होकर रोज इस खुदाई को देखते थे. इनमें से कई लोगों के घरवाले या दोस्त महीनों या वर्षों से 'गुम' हैं. वे इस पवित्र मिट्टी के ढेर में अपने उन सगे संबंधियों की 'मिट्टी' तलाश रहे थे. ऐसे सभी मामलों में आतंकवादियों की गोली के डर से पुलिस के पास शिकायत भी दर्ज नहीं कराई गई थी. अमृतसर नगर पुलिस के पास पिछले चार वर्षों में स्वर्णमंदिर से सिर्फ दो दर्शनार्थियों के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज है. मंदिर में और लोग गायब हुए थे यह बात मलबे से निकलने वाली लाशों की संख्या से पता चलती है. साफ है कि स्वर्णमंदिर परिसर में आतंकवादी जिस पैमाने पर अपने विरोधियों का सफाया कर रहे थे उससे पुलिस एकदम अनजान थी.

एसएसपी सुरेश अरोड़ा कहते हैं, "मैं अंदाजा नहीं लगा सकता कि अभी और कितने लोगों की लाशें अंदर दबी पड़ी हैं." अभी तीन चौथाई मलबे को साफ किया जाना बाकी है. और लाशों का मिलना भी जारी है. इसलिए ऐसा अनुमान लगाना बेकार ही है. लेकिन एक बात तय है कि अब तक सिखों के इस सबसे पवित्र तीर्थ स्थल को इतना अपवित्र पहले कभी नहीं किया गया था. —विपुल मुद्गल

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मध्य प्रदेश

चौथे खंभे को जमीन

राज्य के अखबार मालिकों के लिए सारे नियम-कानून ताक पर

लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले प्रेस पर मध्य प्रदेश सरकार कुछ ज्यादा ही मेहरबान लगती है. अखबार मालिकों ने लगभग 20 करोड़ रु. की जमीन सरकार से औने-पौने भाव में (बाजार भाव के तीसवें हिस्से में) खरीद-कर धमाका जैसा तो कर ही दिया. लगता है अभी और कुछ सरकारी झोली से वे पा जाएंगे. मुख्यमंत्री सचिवालय में गई एक फाइल को हरी झंडी मिलने की कसर है और फिर उनके पौ-बारह.

यदि उस फाइल के प्रस्ताव स्वीकृत हो जाते हैं तो राज्य के विभिन्न शहरों में प्रेस परिसरों की जमीन के मनमाने इस्तेमाल की उन्हें छूट मिल जाएगी. अखबारों के मालिक अब तक तो पट्टों के नियमों को तोड़कर भारी मुनाफा कमाते रहे ही हैं, अब उन्हें इसके लिए सरकारी स्वीकृति मिल जाएगी. मजेदार बात तो यह है कि जिन व्यक्तियों को इससे फायदा होगा उनमें आवास और पर्यावरणमंत्री विष्णु राजोरिया भी शामिल होंगे.

मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के करीबी राजोरिया को 1982 में एक प्लॉट बाजार भाव के मुकाबले काफी कम कीमत पर इस बिना पर मिला था कि वे एक दशक पहले बंद हो गई पत्रिका 'शिखर वार्ता' को फिर शुरू करना चाहते थे. प्लॉट में बनी दोमंजिली इमारत का एक हिस्सा ही पत्रिका (जिसकी छपाई दिल्ली में होती है) कार्यालय के लिए रखा गया. बाकी हिस्सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक को तीस हजार रु. महीने किराए पर देकर राजोरिया ने सभी नियमों को ताक पर रख दिया.

इस साल फरवरी में मंत्री बनने से पूर्व राजोरिया जमीन के पट्टों से संबंधित कानूनों को बदलने के लिए आवाज उठाने वालों में शामिल थे. भोपाल विकास प्राधिकरण (बीडीए) को, जिसने प्रेस कांप्लेक्स में प्लॉट पट्टे पर दिए हुए हैं, भेजे एक संदेश में राजोरिया ने कहा था, "कांप्लेक्स में भवनों को किराए पर उठाने के बारे में स्पष्ट नीति होनी चाहिए." अब आवास और पर्यावरण-मंत्री होने के कारण बीडीए उन्हीं के अधीन है. वे इस महत्वपूर्ण निर्णय को प्रभावित करने की स्थिति में हैं. लेकिन पिछले पखवाड़े जब फाइल उनके पास लाई गई तो उन्होंने उसे मुख्यमंत्री के पास भिजवाने के आदेश दे दिए. राजोरिया कहते हैं, "मैंने खुद निर्णय इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरी पत्रिका भी इसमें शामिल थी."

कानून तोड़ने वालों में राजोरिया का ही नाम नहीं है. और भी कई प्रेस मालिक नियमों को बेधड़क तोड़ रहे हैं. कइयों ने जमीन किसी और के नाम हस्तांतरित कर दी है, कइयों ने परिसर को ही किराए पर उठा दिया है, और ज्यादातर लोगों ने तो जमीन मिलने के छह साल बाद भी कोई निर्माण शुरू नहीं करवाया है. कई लोगों ने तो जमीन की रकम भी अभी नहीं चुकाई है. सामान्य परिस्थितियों में इनमें से एक भी नियम का उल्लंघन आबंटन रद्द करने के लिए काफी होता, लेकिन अखबारों के मालिक सरकारी हलकों में अपने असर के कारण बचे हुए हैं. कई-कई कानून तोड़ने के बाद भी अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है.

यह घोटाला पहली बार 1981 में सामने आया था. जब राज्य सरकार ने दो प्रेस कांप्लेक्स बनवाए—एक भोपाल में और दूसरा इंदौर में. बाद में जबलपुर और रायपुर में भी प्रेस कांप्लेक्स बनाए गए. प्रेस कांप्लेक्स के प्लॉटों के लिए भोपाल और इंदौर के मास्टर प्लान में परिवर्तन भी लाजिमी था. भोपाल के सबसे महंगे इलाके में व्यावसायिक कांप्लेक्स के लिए आरक्षित 27 एकड़ जमीन पर प्रेस कांप्लेक्स बनाया गया. और इंदौर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर शैक्षिक संस्थानों और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आरक्षित 20 एकड़ जमीन अखबार मालिकों को सौंप दी गई.

भोपाल में 'शिखर वार्ता' की इमारत

औने-पौने भाव में अखबारों को मिली जमीन के मनमाने इस्तेमाल का प्रस्ताव पास हुआ तो फायदा उठाने वालों में मंत्री विष्णु राजोरिया भी होंगे

जमीन की कीमतों के मामले में भी बहुत घोटाला हुआ है. भोपाल में अखबारों को एक लाख रु. प्रति एकड़ की दर से जमीन दी गई, जबकि बाजार में यह दर 44 लाख रु. प्रति एकड़ थी. इंदौर में भी कीमतें 2.95 प्रति वर्गफुट से लेकर 7 रु. प्रति वर्गफुट के बीच थीं. कीमतें इस बात पर निर्भर करती थीं कि जमीन का आबंटन कब किया गया. अभी हाल ही में इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) ने अपेक्षाकृत ज्यादा दामों—85 रु. प्रति वर्गफुट—के हिसाब से जमीन नीलाम की. जबलपुर और रायपुर में भी अखबारों को औने-पौने दामों में जमीन दी गई.

इस योजना से सरकार को भारी नुकसान हुआ. यदि जमीन की नीलामी की गई होती तो 20 करोड़ रु. मिल सकते थे. फिर, बीडीए ने उस व्यावसायिक कांप्लेक्स

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

के विकास पर 45 लाख रु. खर्च किए थे, जिसे अखबारवालों ने सिर्फ 27 लाख रु. में खरीदा. और इंदौर में तो आईडीए उस क्षेत्र के विकास पर 20.95 लाख रु. खर्च कर चुकी है. यह बमुश्किल पट्टे की फीस में मिली राशि के बराबर है.

सरकार की इस उदारता का लाभ 'टाइम्स ऑफ इंडिया', 'इंडियन एक्सप्रेस', 'फ्री प्रेस जर्नल' और 'नई दुनिया' जैसे नामी-गिरामी अखबारों ने ही नहीं, छोटे अखबारों ने भी खूब उठाया. इनमें कुछ हैं—'साप्ताहिक बिंदास', 'स्वदर्शन' और 'मालवा समाचार' और विपक्ष में भाजपा का 'स्वदेश' जैसा अखबार. यहां तक कि 'भास्कर' और 'नवभारत' को भी, जिनके

शरद पंडित

'नवीन इंदौर' की इमारतः फायदेमंद सौदा

भोपाल में निजी परिसर हैं, एक-एक एकड़ जमीन मिल गई. सरकार के इस उदार रवैये से नियमों का उल्लंघन होना ही था.

पट्टे की शर्तें कुछ इस प्रकार हैं—

- यदि आबंटन के एक पखवाड़े के भीतर प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं होती तो आबंटन रद्द समझा जाएगा.
- पूरी कीमत चुकाए बिना जमीन पर कब्जा नहीं किया जा सकता. और न ही पट्टे के करारनामे पर हस्ताक्षर हो सकते हैं.
- छह महीने के भीतर निर्माण योजना और साल भर में निर्माण नहीं शुरू होता तो आबंटन रद्द हो जाएगा.
- परिसर को किराये पर नहीं रखा जा सकता. और न ही बिना इजाजत के पट्टा किसी के नाम किया जा सकता है.

लेकिन वास्तविकता इससे बिलकुल उलट है. 'दैनिक दोपहर' और 'मालवा अंचल' जैसे अखबारों ने छह साल बाद तक भी रकम का भुगतान नहीं किया है. लेकिन जमीन पर उनका कब्जा ज्यों का त्यों है. सबसे बढ़िया उदाहरण तो इंका के मुखपत्र 'नवजीवन' और 'नेशनल हेरल्ड' के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स ग्रुप का है. इसकी स्थानीय सलाहकार परिषद में बड़े-बड़े नेताओं और सत्तारूढ़ दल के दिग्गजों का जमावड़ा होने के कारण इसके विशेषाधिकार भी जैसे असीमित हैं. इस कंपनी को जुलाई 1981 में भोपाल में 1.14 एकड़ जमीन दी गई थी. लेकिन इसने 7 सितंबर को केवल एक लाख रु. का भुगतान किया, जबकि तब की दर से इसे 1.14 लाख रुपए देने थे. बीडीए के प्रमुख अधिकारी सी.आई. जॉन कहते हैं, "कंपनी ने अभी तक पूरा भुगतान नहीं किया है." यह कैसे संभव हुआ? इसका स्पष्टीकरण नवजीवन के पूर्व प्रबंधक रमेश चौबे, जिन्होंने कंपनी के लिए पट्टे पर दस्तखत किए थे, देते हैं, "यह सब हमारे दबदबे के कारण हुआ."

पट्टे की एक शर्त यह भी है कि यदि छह महीने के अंदर भवन का नक्शा प्रस्तुत नहीं किया गया और एक साल के अंदर निर्माण शुरू नहीं किया गया तो आबंटन रद्द समझा जाएगा. आज वास्तविकता यह है कि इंदौर प्रेस कांप्लेक्स के 23 प्लॉटों में से अधिकांश खाली पड़े हैं. 'दैनिक दोपहर' के मालिक बी. शुक्ला, जिन्होंने पट्टे की फीस अब तक अदा नहीं की है, कहते हैं, "मेरे पास निर्माण शुरू करवाने के लिए पैसा ही नहीं है."

एक और नियम का उल्लंघन करते हुए ज्यादातर अखबारों ने अपने भवनों को किराए पर उठा दिया है. अपनी इमारत को किराए पर उठाने में आवास मंत्री राजोरिया का नाम सबसे ऊपर है. वे कहते हैं कि उन्होंने अनुमति के लिए बीडीए को कई बार लिखा था, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला. इस नियम को तोड़ने वाले दूसरे अखबार हैं—'दैनिक भास्कर' जिसने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को 18,000 रु. महीने पर अपनी बिल्डिंग किराए पर दे रखी है, 'अपनी दुनिया' जिसने राज्य सिंचाई विभाग को 6,000 रु. महीने पर इमारत की दो मंजिलें किराए पर दी हैं, और 'सतपुड़ा वाणी' जिसने अपना परिसर एक राष्ट्रीयकृत बैंक को किराए पर दे रखा है. 'अपनी दुनिया' के मालिक ओ. खंडेलवाल कहते हैं, "मौजूदा हालात बहुत गड़बड़ हैं, इन्हें जरूर बदला जाना चाहिए."

लेकिन सबसे शर्मनाक मामला प्लाटों की उस फर्जी अदला-बदली का है, जो हाल में प्रकाश में आया है. इनमें सबसे विवादास्पद मामला 'साप्ताहिक बिंदास' और इंदौर के सांध्य दैनिक 'नवीन इंदौर' का है. 'नवीन इंदौर' ने साप्ताहिक 'बिंदास' को दी गई जमीन पर अपना भवन बनाया है. झांसा देने के लिए के लिए यह तरकीब अपनाई गई. इसके संपादक रवींद्र निगम बताते हैं, "हम बिंदास पब्लिकेशन के भागीदार बन गए थे. और हमने अपने हिस्से के आधे प्लॉट पर बिल्डिंग बनवा ली. भागीदारी छह महीने बाद खत्म हो गई. 'बिंदास' के मालिक जिन्हें शुरू में जमीन दी गई थी, अखबार शुरू करने इंदौर नहीं जाना चाहते थे. फिर पिछले साल 'नवीन इंदौर' के मालिकों ने बंबई के उस साप्ताहिक का नाम दो लाख रु. में खरीद लिया. निगम बताते हैं कि इस तरह उन्होंने 14,000 वर्गफुट का पूरा प्लॉट हथिया लिया. बदले में बिंदास के संपादक को मोटा मुनाफा मिला.

ऐसा ही मामला अब बंद हो चुकी समाचार एजेंसी समाचार भारती का है. इसके पूर्व महाप्रबंधक राम प्रसाद सूद ने चौबे के साथ करार किया कि वे भोपाल प्रेस कांप्लेक्स में एजेंसी का प्लॉट पावर ऑफ एटार्नी के आधार पर उन्हें दे देंगे. इस समझौते के अनुसार समाचार भारती को 9,000 वर्गफुट में से अपने इस्तेमाल के लिए 500 वर्गफुट जगह मिलनी थी. ये समझौते पट्टे की शर्तों के खिलाफ हैं.

लेकिन सरकार इन धांधलियों की जांच करने के मूड में कतई नहीं दिखती. इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि खुद आवासमंत्री इन नियमों का सरेआम उल्लंघन कर रहे हैं. और अब वे इस उल्लंघन को कानूनी जामा पहनाना चाहते हैं. यदि सब कुछ ठीकठाक चलता रहा तो अखबार के मालिक जो अब तक छिपकर नियमों को तोड़ रहे थे, अब सरकारी अनुमति से खुलकर नियम तोड़ने लगेंगे.

—नरेंद्र कुमार सिंह, इंदौर में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कहा था, "तब तो हमें मजूमदार (यानी त्रिपुरा के मुख्यमंत्री सुधीररंजन मजूमदार जो कुछ महीने पहले मार्क्सवादियों को पछाड़ कर सत्ता में आए थे) को बुलाना पड़ेगा." आलोचकों का मानना है कि दासमुंशी के लिए प्रधानमंत्री का आशय साफ था—कुछ करके दिखाओ या पद छोड़ दो.

पिछली विधानसभा में इंका विधायक दल के पदों से हटाए गए सोमेन मित्रा और सुब्रत मुकर्जी सरीखे अपमानित नेता तुरंत ही सक्रिय हो गए. राज्य इकाइयों और पार्टी संगठन के नेताओं की दिल्ली में हुई एक बैठक में दासमुंशी पर संगठन की उपेक्षा करने, पार्टी के युवा छात्र और महिला संगठनों को निष्क्रिय बना देने तथा पश्चिम बंगाल में वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करने के आरोप लगाए गए.

उधर कलकत्ता में विपक्ष के नेता अब्दुस्सत्तार ने भी आलोचनात्मक रुख अपनाया. उन्होंने कहा, "अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं रह गई है. और नेता एक-दूसरे के खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं."

लेकिन दासमुंशी का भविष्य अब मार्क्सवादियों से निबटने की उनकी कामयाबी पर निर्भर हैं. आलोचकों का कहना है कि इस मामले में उनका रिकार्ड बहुत अच्छा नहीं है. उनके मुताबिक रॉडन पार्क के मुद्दे पर आंदोलन के अलावा पार्टी के किसी भी कार्यक्रम को जन समर्थन नहीं मिला है.

दासमुंशी के खिलाफ मुहिम में तेजी आने के साथ ही एक ऐसे नेता की तलाश शुरू हो गई है जो राज्य में मार्क्सवादियों का किला ध्वस्त करने में पार्टी का नेतृत्व कर सके. जो नए नाम लिए जा रहे हैं उनमें पूर्व केंद्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री अब्दुल गनी खां चौधरी और केंद्रीय राजस्व राज्यमंत्री अजीत पांजा शामिल हैं. बताया जाता है कि पांजा भी इस पद के लिए गनी खां चौधरी का समर्थन कर रहे हैं. उधर गनी खां चौधरी के समर्थक भी मार्क्सवादियों से जूझने का कार्यक्रम बनाने में जुटे हुए हैं.

लेकिन इंका द्वारा घोषित 'एक व्यक्ति, एक पद' की नीति के बावजूद दासमुंशी अभी पद छोड़ने को तैयार नहीं दिखते. उधर उनके विरोधियों का मानना है कि देर-सवेर उन्हें यह कुर्सी खाली करनी ही होगी.

पर नए अध्यक्ष की नियुक्ति से पश्चिम बंगाल इंका में नए समीकरण बनना और नए अंतर्विरोध उभरना एकदम निश्चित है. मार्क्सवादियों की मजबूत पकड़ को देखते हुए फिलहाल यही लगता है कि नए अध्यक्ष को एक साथ दो मोर्चों पर जूझना होगा.

—कमलजीत रतन

गुजरात

सांसत में चौधरी

अपनी ही पार्टीवाले नाराज

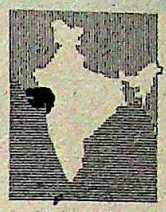

वे न तो कुशल रणनीतिज्ञ माने जाते हैं और ही राजनीति के दिग्गज. इसलिए दो महीने बाद जब गुजरात के मुख्यमंत्री अमर सिंह चौधरी अपने हंगामाखेज कार्यकाल के तीन साल पूरे कर लेंगे तो इससे न सिर्फ राजनैतिक पर्यवेक्षकों को ही बल्कि शायद खुद चौधरी को भी ताज्जुब हो. अपने कार्यकाल के दौरान चौधरी को लगातार आंदोलनों और बार-बार पड़ने वाले अभूतपूर्व सूखे के अलावा अपनी ही पार्टी के असंतुष्ट लोगों के तीखे हमलों का भी सामना करना पड़ा.

अमर सिंह चौधरी

हसमुख पटेल

माधव सिंह सोलंकी

पिछले पखवाड़े गुजरात विश्वविद्यालय क्षेत्रीय शिक्षक संघ की एक उपशाखा अखिल गुजरात नागरिक समिति के गठन से ये हमले और भी तेज हो गए. समिति के सदस्य चौधरी के प्रमुख राजनैतिक प्रतिद्वंद्वी पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी के करीबी माने जाते हैं. उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री ने वडोदरा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के तृतीय वर्ष में पढ़ रहे अपने पुत्र तुषार के नतीजे को प्रभावित करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया है. इसलिए वे चौधरी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं.

दरअसल गुजरात में सत्तारूढ़ पार्टी के अंदर हालत बिलकुल महाराष्ट्र जैसी है. फर्क सिर्फ यह है कि जहां वसंतदादा पाटील खुलेआम मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण की भर्त्सना कर रहे हैं, वहीं सोलंकी ने परदे के पीछे से चौधरी के खिलाफ जेहाद छेड़ रखा है. इस लड़ाई में सोलंकी मुख्य तौर पर राज्य के शिक्षामंत्री हसमुख पटेल को इस्तेमाल कर रहे हैं जिनका ताकतवर विश्वविद्यालय शिक्षक संघ पर खासा नियंत्रण है.

तीन महीने पहले सोलंकी ने विधायकों को 'चौधरी हटाओ' दस्तखत मुहिम के लिए प्रेरित किया था. लेकिन मुहिम एक तो चौधरी के दांवपेचों और दूसरे आलाकमान द्वारा सोलंकी को राज्यसभा टिकट देने से ठप हो गई. लेकिन चुने जाने के बाद सोलंकी फिर चौधरी विरोधी मुहिम में जुट गए.

पटेल की कोशिशों के चलते पिछले महीने शिक्षक संघ ने पदोन्नति संबंधी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी. संघ के अध्यक्ष के.एस. शास्त्री विश्वविद्यालय के गैर-शिक्षक कर्मचारियों का समर्थन पाने में भी कामयाब रहे. शास्त्री इसलिए चौधरी से नाराज बताए जाते हैं क्योंकि पिछले साल कुलपति का पांच वर्षीय कार्यकाल पूरा करने के बाद उन्हें कोई महत्वपूर्ण पद नहीं सौंपा गया है. गैर-शिक्षक कर्मचारियों का समर्थन पाकर शिक्षक संघ के नेताओं ने धमकी दे डाली कि जब तक मांगें पूरी नहीं की जातीं वे विश्वविद्यालय की परीक्षाएं नहीं होने देंगे.

विश्वविद्यालय में कोई कुलपति न होने से 15 दिन तक स्थिति उलझती चली गई. तब जाकर चौधरी ने प्रोफेसर एम. एन. देसाई को कुलपति नियुक्त किया. वे किसी राजनैतिक गुट से नहीं जुड़े हैं. देसाई के कुलपति बनते ही हालात सुधरने लगे. गैर-शिक्षक कर्मचारियों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया जिससे परीक्षाएं करवाने का रास्ता साफ हो गया. लेकिन शिक्षक संघ ने अपनी हड़ताल जारी रखी.

तुषार वाले मुद्दे को उछालते रहने के उद्देश्य से ही समिति का गठन किया गया था ताकि चौधरी पर दबाव बनाए रखा जाए. पर मुख्यमंत्री की परेशानियां इतनी ही नहीं थीं. वे आलाकमान से सोलंकी समर्थक तीन असंतुष्ट मंत्रियों—पटेल, राजस्वमंत्री हरीश महीदा और कृषिमंत्री एम. विजयदास जी—को निकाले जाने की अनुमति हासिल करने में भी नाकाम रहे.

लगातार राजनैतिक दबाव का असर प्रशासन पर भी पड़ा है. लोगों का मानना है कि यदि चौधरी को अपनी गद्दी की फिक्र न करनी पड़ती तो वे कारगर तरीके से सूखे का सामना कर सकते थे. लेकिन व्यावहारिक और सुलझे तरीके से काम करने और विभिन्न जातीय गुटों से समर्थन जुटाने की अपनी क्षमता की वजह से वे अभी तक टिके हुए हैं.

—उदय माहूरकर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कर्ज मेला

बिन मांगे मोती

छिदवाड़ा में 22 करोड़ बंटे

मसुरिया गांव की चोंटी बाई एकदम गदगद थी. छिदवाड़ा में लगे कर्ज मेले ने उसे 'मालामाल' जो कर दिया था. एक बैंक ने उसे बकरी खरीदने के लिए 3000 रुपए का कर्ज दे दिया. कर्ज मेले के शोर, गरमी, धूल और बिन मांगे मिले मोती के 'झटके' से वह सन्न-सी थी.

कुछ हफ्ते पहले सरकारी अधिकारी उसके गांव आए और उससे पूछा कि क्या तुम्हें कर्ज की जरूरत है. उसे समझाया गया कि वह बकरी पालना शुरू कर सकती है. चोंटी बाई ने अपने जीवन में कभी बकरी नहीं पाली थी. लेकिन वह इस आती लक्ष्मी को

आर.सी. साहू

छिदवाड़ा कर्ज मेले में औरतों की भीड़; और (इनसेट में) कमलनाथ

ठुकरा नहीं पाई. कर्ज कैसे उतारोगी, यह पूछे जाने पर वह अचकचा जाती है और कहती है, "क्या वे लोग पैसे वापस भी लेंगे?"

पिछले पखवाड़े दक्षिण-पश्चिमी मध्य प्रदेश के छिदवाड़ा में लगे देश के सबसे बड़े कर्ज मेले में कर्ज पाने वालों में चोंटी बाई जैसे हजारों लोग थे. यह कर्ज मेला इंका सांसद कमलनाथ की पहल पर लगा. वे इस पिछड़े आदिवासी इलाके से ही चुने जाते हैं. उन्होंने इसके लिए तीन महीने तक भागदौड़ की थी. और इसी का नतीजा था कि 50,000 से भी अधिक लोगों के बीच 22 करोड़ रुपए कर्ज के बतौर बांट दिए गए. कमलनाथ ने कहा, "अधिकारियों ने सभी मामलों की जांच करने का कष्ट उठाया. इतने बड़े पैमाने पर बंटे कर्ज में कुछ गड़बड़ियां तो हो ही सकती हैं."

इसमें संदेह नहीं कि यह बड़ा आयोजन था. जिला प्रशासन और बैंकों के अधिकारियों ने इसकी तैयारियां दो महीने पहले से ही शुरू कर दी थीं. उन्होंने जिले भर में 288 केंद्र बनाए थे और वहीं शिविर लगाकर कर्ज पाने वालों की सूची बनाई. छिदवाड़ा के कलक्टर एंथनी डी सा ने कहा, "हमने जिले के सभी 2000 गांवों को इसमें शामिल किया."

परिणाम भी शानदार रहे. जिले के हर तीसरे वनवासी और हरिजन परिवार को कर्ज मिला. जिले के व्यावसायिक और सहकारी बैंकों की 127 शाखाओं ने 17 लाख रुपए से अधिक के कर्ज दिए और सरकार ने कुल 3.21 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी. वित्तमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने कहा, "छिदवाड़ा के विकास की लंबी यात्रा की शुरुआत हो गई है."

निश्चित रूप से कमलनाथ ने अपने चुनाव क्षेत्र के विकास के लिए ही इस कर्ज मेले का आयोजन कराया था. उन्होंने वित्तमंत्री तिवारी और राज्य के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह, राजस्व-मंत्री बिसाहु राम यादव और अन्य वीआईपी लोगों तथा बैंक के बड़े अधिकारियों को जुटाकर अपने 'प्रभाव' का प्रदर्शन भी किया. प्रशासन ने भी लोगों को सभी जगह से बैलगाड़ियों पर लाने और उन्हें रियायती दर पर खाना उपलब्ध कराने का काम सफलतापूर्वक किया.

7 जून को, जिस दिन कर्ज मेला लगा, सिर्फ दस फीसदी लोगों को ही क़र्ज मिला. अन्य लोगों को तीन महीने के अंदर लगने वाले 172 शिविरों से कर्ज मिलेगा. यह मेला इंकाई 'तमाशा' था, इसके बावजूद सब कुछ सचमुच व्यवस्थित हुआ. शासक दल और युवक कांग्रेस की ओर से लोगों के स्वागत के लिए लगाए गए पोस्टरों से सारा शहर भरा पड़ा था. कर्ज लेने वालों को लाने वाली गाड़ियों पर इंका का झंडा लगा था. दरअसल पार्टी के पदाधिकारियों से कहा गया था कि वे वीआईपी लोगों का स्वागत करें. लोगों के बीच अच्छी छवि बनाने के लिए 22 करोड़ रुपए की क्या बिसात है. और यह रकम तब और भी कम लगती है जब पैसा अपनी जेब का न होकर किसी और का हो.

—नरेंद्र कुमार सिंह, छिदवाड़ा में

पश्चिम बंगाल

मुंशी पर मार

इंका अध्यक्ष की कुर्सी डगमग

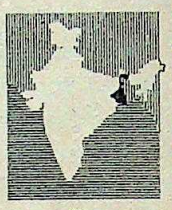

पश्चिम बंगाल इंका अध्यक्ष की कुर्सी डगमगाती दिखती है. केंद्रीय वाणिज्य राज्य-मंत्री प्रियरंजन दासमुंशी पर यह पद छोड़ने के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है.

उन्हें अपदस्थ करने की इस मुहिम में कई बड़े और छोटे नेताओं का एक ऐसा गुट सक्रिय है जिसकी पहुंच पार्टी आलाकमान तक भी है. पिछले पखवाड़े इंका महासचिव ऑस्कर फर्नांडीस की दो बार कलकत्ता उड़ान से इंका हलकों में अटकलें लगाई जाने लगी कि राज्य नेतृत्व में फेरबदल बस अब होने ही वाला है. दासमुंशी पर मुख्य आरोप है कि वे मार्क्सवादियों का आधार कमजोर नहीं कर पाए. उनमें नेतृत्व की क्षमता नहीं है और वे संकीर्ण गुटबंदी को बढ़ावा देते हैं.

जून 1986 में राज्य पार्टी का अध्यक्ष बनने के तुरंत बाद दासमुंशी ने अपने दुश्मन बनाने शुरू कर दिए थे. पार्टी की जिला और ब्लॉक स्तर की समितियों और युवा शाखा को फिर से गठित करने की अपनी धुन में उन्होंने कई नेताओं से नाराजगी मोल ले ली थी.

दासमुंशी

पुनर्गठन में उन्होंने ज्यादातर अपने उन समर्थकों को प्रमुखता दी थी जो कांग्रेस (स) से आए थे. इससे दूसरे नेता उपेक्षित महसूस करने लगे. दासमुंशी के प्रबल समर्थक रहे विधायक साधन पांडेय कहते हैं, "उन्हें तो अंदर ही अंदर डर सताता है. उनका गुट मुख्य धारा से कभी जुड़ नहीं पाया."

उनके खिलाफ दबा आक्रोश अब खुलकर सामने आने लगा है. आलोचकों ने इसके लिए संकेत पार्टी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री राजीव गांधी के उस भाषण से लिया है जो उन्होंने मद्रास के निकट मरैमलै नगर में हुए इंका महासमिति के सम्मेलन में दिया था.

बताया जाता है कि सम्मेलन में जब दासमुंशी ने प्रधानमंत्री से राज्य पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के असहयोग और राज्य सरकार द्वारा वामपंथी दलों को दी गई मदद का रोना रोया तो राजीव ने व्यंग्य करते हुए

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कहा था, "तब तो हमें मजूमदार (यानी त्रिपुरा के मुख्यमंत्री सुधीररंजन मजूमदार जो कुछ महीने पहले मार्क्सवादियों को पछाड़ कर सत्ता में आए थे) को बुलाना पड़ेगा." आलोचकों का मानना है कि दासमुंशी के लिए प्रधानमंत्री का आशय साफ था—कुछ करके दिखाओ या पद छोड़ दो.

पिछली विधानसभा में इंका विधायक दल के पदों से हटाए गए सोमेन मित्रा और सुब्रत मुकर्जी सरीखे अपमानित नेता तुरंत ही सक्रिय हो गए. राज्य इकाइयों और पार्टी संगठन के नेताओं की दिल्ली में हुई एक बैठक में दासमुंशी पर संगठन की उपेक्षा करने, पार्टी के युवा छात्र और महिला संगठनों को निष्क्रिय बना देने तथा पश्चिम बंगाल में वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करने के आरोप लगाए गए.

उधर कलकत्ता में विपक्ष के नेता अब्दुस्सत्तार ने भी आलोचनात्मक रुख अपनाया. उन्होंने कहा, "अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं रह गई है. और नेता एक-दूसरे के खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं."

लेकिन दासमुंशी का भविष्य अब मार्क्सवादियों से निबटने की उनकी कामयाबी पर निर्भर हैं. आलोचकों का कहना है कि इस मामले में उनका रिकार्ड बहुत अच्छा नहीं है. उनके मुताबिक रॉडन पार्क के मुद्दे पर आंदोलन के अलावा पार्टी के किसी भी कार्यक्रम को जन समर्थन नहीं मिला है.

दासमुंशी के खिलाफ मुहिम में तेजी आने के साथ ही एक ऐसे नेता की तलाश शुरू हो गई है जो राज्य में मार्क्सवादियों का किला ध्वस्त करने में पार्टी का नेतृत्व कर सके. जो नए नाम लिए जा रहे हैं उनमें पूर्व केंद्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री अब्दुल गनी खां चौधरी और केंद्रीय राजस्व राज्यमंत्री अजीत पांजा शामिल है. बताया जाता है कि पांजा भी इस पद के लिए गनी खां चौधरी का समर्थन कर रहे हैं. उधर गनी खां चौधरी के समर्थक भी मार्क्सवादियों से जूझने का कार्यक्रम बनाने में जुटे हुए हैं.

लेकिन इंका द्वारा घोषित 'एक व्यक्ति, एक पद' की नीति के बावजूद दासमुंशी अभी पद छोड़ने को तैयार नहीं दिखते. उधर उनके विरोधियों का मानना है कि देर-सवेर उन्हें यह कुर्सी खाली करनी ही होगी.

पर नए अध्यक्ष की नियुक्ति से पश्चिम बंगाल इंका में नए समीकरण बनना और नए अंतर्विरोध उभरना एकदम निश्चित है. मार्क्सवादियों की मजबूत पकड़ को देखते हुए फिलहाल यही लगता है कि नए अध्यक्ष को एक साथ दो मोर्चों पर जूझना होगा.

—कमलजीत रतन

गुजरात

सांसत में चौधरी

अपनी ही पार्टीवाले नाराज

वे न तो कुशल रणनीतिज्ञ माने जाते हैं और ही राजनीति के दिग्गज. इसलिए दो महीने बाद जब गुजरात के मुख्यमंत्री अमर सिंह चौधरी अपने हंगामाखेज कार्यकाल के तीन साल पूरे कर लेंगे तो इससे न सिर्फ राजनैतिक पर्यवेक्षकों को ही बल्कि शायद खुद चौधरी को भी ताज्जुब हो. अपने कार्यकाल के दौरान चौधरी को लगातार आंदोलनों और बार-बार पड़ने वाले अभूतपूर्व सूखे के अलावा अपनी ही पार्टी के असंतुष्ट लोगों के तीखे हमलों का भी सामना करना पड़ा.

अमर सिंह चौधरी

हसमुख पटेल

माधव सिंह सोलंकी

पिछले पखवाड़े गुजरात विश्वविद्यालय क्षेत्रीय शिक्षक संघ की एक उपशाखा अखिल गुजरात नागरिक समिति के गठन से ये हमले और भी तेज हो गए. समिति के सदस्य चौधरी के प्रमुख राजनैतिक प्रतिद्वंद्वी पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी के करीबी माने जाते हैं. उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री ने वडोदरा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के तृतीय वर्ष में पढ़ रहे अपने पुत्र तुषार के नतीजे को प्रभावित करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया है. इसलिए वे चौधरी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं.

दरअसल गुजरात में सत्तारूढ़ पार्टी के अंदर हालत बिलकुल महाराष्ट्र जैसी है. फर्क सिर्फ यह है कि जहां वसंतदादा पाटील खुलेआम मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण की भर्त्सना कर रहे हैं, वहीं सोलंकी ने परदे के पीछे से चौधरी के खिलाफ जेहाद छेड़ रखा है. इस लड़ाई में सोलंकी मुख्य तौर पर राज्य के शिक्षामंत्री हसमुख पटेल को इस्तेमाल कर रहे हैं जिनका ताकतवर विश्वविद्यालय शिक्षक संघ पर खासा नियंत्रण है.

तीन महीने पहले सोलंकी ने विधायकों को 'चौधरी हटाओ' दस्तखत मुहिम के लिए प्रेरित किया था. लेकिन मुहिम एक तो चौधरी के दांवपेचों और दूसरे आलाकमान द्वारा सोलंकी को राज्यसभा टिकट देने से ठप हो गई. लेकिन चुने जाने के बाद सोलंकी फिर चौधरी विरोधी मुहिम में जुट गए.

पटेल की कोशिशों के चलते पिछले महीने शिक्षक संघ ने पदोन्नति संबंधी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी. संघ के अध्यक्ष के.एस. शास्त्री विश्वविद्यालय के गैर-शिक्षक कर्मचारियों का समर्थन पाने में भी कामयाब रहे. शास्त्री इसलिए चौधरी से नाराज बताए जाते हैं क्योंकि पिछले साल कुलपति का पांच वर्षीय कार्यकाल पूरा करने के बाद उन्हें कोई महत्वपूर्ण पद नहीं सौंपा गया है. गैर-शिक्षक कर्मचारियों का समर्थन पाकर शिक्षक संघ के नेताओं ने धमकी दे डाली कि जब तक मांगें पूरी नहीं की जातीं वे विश्वविद्यालय की परीक्षाएं नहीं होने देंगे.

विश्वविद्यालय में कोई कुलपति न होने से 15 दिन तक स्थिति उलझती चली गई. तब जाकर चौधरी ने प्रोफेसर एम. एन. देसाई को कुलपति नियुक्त किया. वे किसी राजनैतिक गुट से नहीं जुड़े हैं. देसाई के कुलपति बनते ही हालात सुधरने लगे. गैर-शिक्षक कर्मचारियों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया जिससे परीक्षाएं करवाने का रास्ता साफ हो गया. लेकिन शिक्षक संघ ने अपनी हड़ताल जारी रखी.

तुषार वाले मुद्दे को उछालते रहने के उद्देश्य से ही समिति का गठन किया गया था ताकि चौधरी पर दबाव बनाए रखा जाए. पर मुख्यमंत्री की परेशानियां इतनी ही नहीं थीं. वे आलाकमान से सोलंकी समर्थक तीन असंतुष्ट मंत्रियों—पटेल, राजस्वमंत्री हरीश महीदा और कृषिमंत्री एम. विजयदास जी—को निकाले जाने की अनुमति हासिल करने में भी नाकाम रहे.

लगातार राजनैतिक दबाव का असर प्रशासन पर भी पड़ा है. लोगों का मानना है कि यदि चौधरी को अपनी गद्दी की फिक्र न करनी पड़ती तो वे कारगर तरीके से सूखे का सामना कर सकते थे. लेकिन व्यावहारिक और सुलझे तरीके से काम करने और विभिन्न जातीय गुटों से समर्थन जुटाने की अपनी क्षमता की वजह से वे अभी तक टिके हुए हैं.

—उदय माहूरकर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

टी वी की सर्विस होनी चाहिए तब, जब यह काम कर रहा हो पूरी कुशलता से.

इसे हम कहते है प्रीवेंटिव मेन्टेनेन्स यानी खराबी की रोकथाम करने वाली देखभाल. जिसे हम हर पिरामिड टी वी के लिए बिल्कुल मुफ़्त करते है.

पहले वर्ष के दौरान, हर तीन महीने में हमारा इंजीनियर आपके पास आएगा.

वह आपके एन्टीना को ठीक-ठाक करेगा, आपके सेट की सफ़ाई करेगा, और पूरी तरह उसकी जांच-पड़ताल करेगा. यदि कोई छोटी-मोटी खराबी होगी, तो उसी वक़्त ठीक कर देगा.

ये तो हमारी सेवाओं का केवल एक छोटा सा हिस्सा है.

आपका पिरामिड टी वी घर पर पहुंचने के दो हफ़्ते बाद ही कंपनी का इंजीनियर आपके घर पहुंचकर देखेगा कि आपका सेट सही तरीके से लगाया गया है या नहीं? और यह बढ़िया ढंग से काम कर रहा है या नहीं?

और इसके बाद भी यदि आपको कोई परेशानी हो तो फ़ोन कीजिए, हमारा इंजीनियर २४ घंटे या इससे भी कम वक़्त में आपकी सेवा में मौजूद होगा!

बदकिस्मती से कभी आपका सेट मरम्मत के लिए सर्विस सेन्टर ले जाना पड़े तो बदले में हम आपको दूसरा सेट देंगे. यानी आपको अपना मनपसंद कार्यक्रम 'चित्रहार' देखने के लिए पड़ोसी का दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी!

दरअसल गारंटी है किसकी सुरक्षा : आपकी या निर्माता की?

आज ज़्यादातर गारंटियां देखकर आप सोचते होंगे कि आख़िर इसका मतलब क्या है?

इनमें लंबी-चौड़ी सूची तो उन नामों की होती है जिनकी गारंटी नहीं दी जाती.

और जिस सबसे ज़रूरी चीज़ के बारे में निर्माता जान-बूझकर ख़ामोश रहते हैं: वह है पिक्चर ट्यूब.

लेकिन ठीक इसके विपरीत पिरामिड की गारंटी इसके ख़रीदारों को ध्यान में रखकर दी जाती है.

बग़ैर किसी संशय के, पूरी तरह बेनुक्स गारंटी. जिसमें पिक्चर ट्यूब भी शामिल होती है.

ऐसी गारंटी जो आपको सुरक्षा देती है... न कि निर्माता को.

वेव सॉल्डरिंग : भारत के १०० से भी अधिक टी वी जो नहीं करते.

इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनों के लिए वेव सॉल्डरिंग बिल्कुल वैसी ही ज़रूरी चीज़ है जैसी कि कपड़ों के लिए सिलाई : यानी हर जोड़ पूरे एहतियात और मज़बूती के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए.

बदकिस्मती से भारत के अधिकांश टी वी में आज भी सॉल्डरिंग हाथों से की जाती है. एक ऐसा घटिया तरीका जो टी वी की परिपूर्णता में सबसे बड़ी रुकावट है.

कुछ गिने-चुने ब्राण्डों में केवल पिरामिड ही ऐसा एकमात्र टी वी है जिसमें इस्तेमाल की जाती है वेव सॉल्डरिंग– पूरी तरह अचूक एक ऐसी स्वचालित प्रक्रिया जो दिलाती है सौ-फ़ीसदी बेहतरीन कामगिरी.

बिल्कुल वही फ़र्क, जो मशीन की सिलाई और हाथ से की जानेवाली कच्ची सिलाई के बीच होता है.

अधिकार से इंतज़ार तक : लगातार ४८ घंटे का कड़ा परीक्षण दौर.

हर पिरामिड टी वी को गुज़रना होता है लगातार ४८ घंटे चलते रहने की कड़ी अग्नि परीक्षा से.

इस तरह की अग्नि परीक्षा के कुछ अपने फ़ायदे है.

सेट में किसी तरह की अनियमितता या गड़बड़ी हो तो वह छुप नहीं सकती और उस को तुरंत दुरुस्त किया जा सकता है. इस प्रकार यह पक्का हो जाता है कि पिरामिड का कोई भी दोषपूर्ण सेट बाजार में आ ही नहीं सकता.

ज़्यादातर टी वी इस तरह का परीक्षण तो करते है पर सिर्फ़ ६ घंटे तक. कुछ एक १२ घंटे तक. और कुछ २४ घंटे... लेकिन इससे अधिक नहीं.

पिरामिड में एक ख़ासियत नहीं जो ज़्यादातर दूसरे टी वी में होती हैं : धूल-गर्द.

धूल-गर्द इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट की सबसे ख़तरनाक दुश्मन है.

बदकिस्मती से ज़्यादातर टी वी जब कारखाने से निकलते है तो इनमें धूल या गर्द मौजूद होती है.

लेकिन ठीक इसके विपरीत पिरामिड कारखाने में तकनीकी साफ़-सफ़ाई के सबसे ऊंचे स्तर को कायम रखा जाता है. तभी तो हर पिरामिड टी वी तैयार होता है पूरे धूल नियंत्रित वातावरण में.

पिरामिड : न कोई चिंता, न कोई ग़म इस टी वी में ऐसा दम.

टी वी ख़रीदते समय आपका पहला सवाल यही होता है– "इसके निर्माता कौन है?"

और हमारे पास है इसका बहुत ही ठोस और विश्वसनीय जवाब. क्योंकि पिरामिड के निर्माण के पीछे है ६०० करोड़ रुपये की बिक्री का– लालभाई ग्रुप.

बरसों की मेहनत और लगन के बलबूते पर लालभाई ग्रुप ने टेक्सटाइल्स, एअरकंडीशन से, केमिकल्स, इंजीनियरिंग और फ़ायनान्स के क्षेत्र में ऊंचे दर्जे के उत्पादन तैयार करके अपनी खास पहचान बनाई है.

इसीलिए तो जब आप पिरामिड खरीदते है तो आपको किसी बात की फ़िक्र नहीं करनी पड़ती.

क्योंकि आपकी तमाम फ़िक्रों का बोझ पहले ही उठा लिया है लालभाई ग्रुप ने.

पिरामिड पेश करते है पिरामिड २००० ई, पिरामिड २००० आर, पिरामिड प्लस (रिमोट और नॉन रिमोट), पिरामिड परफ़ेक्ट और पिरामिड २०९ जे कलर में. पिरामिड १४२, पिरामिड १४५ टी और पिरामिड १४५ ई, १४" ब्लैक एण्ड व्हाईट पोर्टेबुल में, पिरामिड ५१० और पिरामिड ५११ २०" ब्लैक एण्ड व्हाईट में.

पिरामिड... इसमें कोई शक नहीं.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

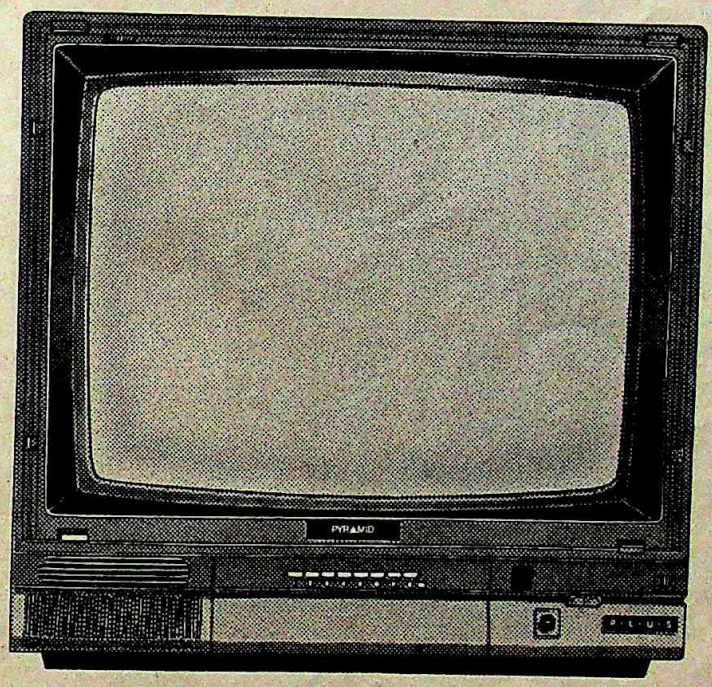

PYRAMID
COLOUR TELEVISION

जापानी टेक्नालॉजी का उत्पादन.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ओडीसा

दामाद का दबदबा

मुख्यमंत्री पटनायक के संपादक दामाद पर आरोपों की बौछार

उन्हें जेहादी संपादक तो नहीं कहा जा सकता. पर 38 वर्षीय सोमैया रंजन पटनायक यह जरूर जानते हैं कि हमला कैसे बोला जाए. वे पांच साल पुराने ओड़िया दैनिक 'संवाद' के संपादक ही नहीं, मुख्यमंत्री जानकीबल्लभ पटनायक के दामाद होने के कारण खासी हैसियत भी रखते हैं.

प्रवक्ता से संपादक बने सोमैया ने पिछले महीने अपने कट्टर विरोधी और राज्य के शिक्षामंत्री जदुनाथ दास महापात्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. 60,000 प्रसार संख्या वाले इस अखबार ने पहले पेज पर हायर सेकेंडरी परीक्षा का आउट हुआ पूरा पर्चा छाप दिया. यह पर्चा उसी दिन होना था. वैसे भी यह परीक्षा दुबारा कराई जा रही थी क्योंकि मार्च-अप्रैल में भी पर्चा आउट होने की वजह से परीक्षा स्थगित कर देनी पड़ी थी. अखबार ने पर्चा आउट होने की सारी गड़बड़ी का दोष महापात्र के ही मत्थे मढ़ दिया.

खुद मंत्री का मानना है कि 'संवाद' की यह कार्रवाई उन्हें परेशान करने के लिए थी. अखबार में पर्चा छपते ही शिक्षा विभाग ने परीक्षा रुकवा दी. इसके बाद शिक्षा सचिव प्यारी मोहन महापात्र ने मुख्यमंत्री को एक गोपनीय चिट्ठी में सलाह दी कि 'गैरकानूनी' तौर पर पर्चा हासिल करने और उसे प्रकाशित करने के लिए 'संवाद' और उसके संपादक के खिलाफ कार्रवाई की जाए. पर मुख्यमंत्री का कहना है कि उन्हें ऐसी कोई चिट्ठी नहीं मिली. कई तीखे विवादों में फंसे सोमैया रंजन अपने बचाव में कहते हैं, "महापात्र से मेरा कोई निजी विरोध नहीं है. मैं तो बस इतना ही चाहता हूं कि पर्चे बार-बार आउट होने के लिए किसी को तो जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए."

पर संपादक और मंत्री के अरसे से चले आ रहे खट्टे रिश्तों की वजह से बहुत से लोग इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं. शिक्षा विभाग के अधिकारियों का आरोप है कि सोमैया रंजन शिक्षामंत्री के कड़े विरोध के बावजूद कुछ निजी कॉलेजों की प्रबंध समितियों पर अपना कब्जा जमाने की फिराक में हैं.

अपने आरोप के समर्थन में वे पूर्व उच्च शिक्षा निदेशक दीनबंधु मिश्र के मामले का उदाहरण देते हैं. पिछले साल सोमैया रंजन ने मिश्र के घर में घुसकर उनसे जवाबतलबी की थी कि उन्हें भुवनेश्वर के महर्षि कॉलेज ऑफ नेचुरल लॉ का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया गया. मिश्र के जवाब से संतुष्ट न होने पर सोमैया रंजन गुस्से में भुनभुनाते बाहर निकल गए. कुछ ही समय बाद मिश्र का तबादला करके उन्हें विशेष कार्य अधिकारी बना दिया गया.

सोमैया रंजन आरोपों के प्रति खंडन और टालमटोल की मिश्रित भाषा बोलते हैं. वे कहते हैं, "शिक्षा संस्थाओं में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है और अगर हो भी तो शिक्षा विभाग मुझे कैसे रोक सकता है." उनकी शिकायत है कि "हर कोई (मुझसे) ईर्ष्या करता है."

'ईर्ष्या' की बहुत-सी वजहें भी हैं. 1983 तक सोमैया रंजन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र के प्रवक्ता थे. पर आज वे ही राजनैतिक सत्ता की धुरी बने हुए हैं और छह प्रकाशनों की एक छोटी-मोटी रियासत के सिरमौर हैं. विधायक और मंत्री तक उनका 'आशीर्वाद' पाने आते हैं. कोई भी सांस्कृतिक आयोजन या समिति उनके बिना अधूरी मानी जाती है. 42 संगठनों के प्रमुख सोमैया रंजन दिन भर व्यस्त रहते हैं. राज्य साहित्य अकादमी के एक सदस्य, भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष, और लेखक व प्रकाशक मंच के संयोजक की हैसियत से सोमैया रंजन को राज्य के बारे में बेहतर तरीके से जानने की भूख मिटाने के लिए ढेर सारे मौके मिले हुए हैं.

उधर मुख्यमंत्री पटनायक की नजर में उनके दामाद सोमैया दूध के धुले हुए हैं. हालांकि वे यह मानते हैं कि उनके मुख्यमंत्री होने का फायदा शायद सोमैया रंजन को मिलता हो लेकिन साथ ही वे यह दलील देते हैं, "विभिन्न संगठन उसे इसलिए अपने सिर-आंखों पर बिठाए रखते हैं क्योंकि वह तेज तर्रार है और कई अखबारों का मालिक भी."

लेकिन आलोचकों के हिसाब से मामला सोमैया रंजन को तेजतर्रारी से कुछ ज्यादा ही है. भुवनेश्वर के वकील और जनता पार्टी नेता, 38 वर्षीय स्वराज बिस्वाल कहते हैं, "वे तो ज्यादा-से-ज्यादा सत्ता हासिल करना चाहते हैं." सोमैया रंजन के विरोधियों का कहना है कि लोग उनके दरवाजे पर इसलिए लाइन लगाए रहते हैं क्योंकि वे सरकारी संरक्षण हासिल करने का जरिया हैं. विरोध में सोमैया रंजन कहते हैं, "लोग मेरे पास इसलिए आते हैं क्योंकि मैं उनकी

दफ्तर में सोमैया रंजन: सत्ता की धुरी

ईस्टर्न प्रेस एजेंसी

सोमैया रंजन के अखबार 'संवाद' ने आउट हुआ पर्चा ही छाप दिया. शिक्षामंत्री महापात्र का मानना है कि ऐसा उन्हें राजनैतिक तौर पर परेशान करने के लिए किया गया

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बात सुनता हूं. सवाल यह है कि कितने लोगों ने फायदा उठाया? एक ने भी नहीं."

पर आलोचक इसके लिए कई नाम गिनाते हैं. उनके आरोप हैं:

• सोमैया रंजन जब टैक्सी मालिक संघ के अध्यक्ष बने तो तुरंत ही सरकार ने यह फैसला वापस ले लिया कि निजी टैक्सियों में मीटर लगाना पड़ेगा. पर संपादक का कहना है कि उन्होंने टैक्सी मालिकों को अधिकारियों के आगे अपने मामले की पैरवी किस तरह करें, इतनी ही सलाह दी थी.

• भुवनेश्वर में निजी बसों के मालिक शहर के बाहर से आई बसों के मालिकों से राहदरी वसूलते थे, पुलिस ने इसे रोकने का फैसला किया. आलोचकों का आरोप है कि

ईस्टर्न प्रेस एजेंसी

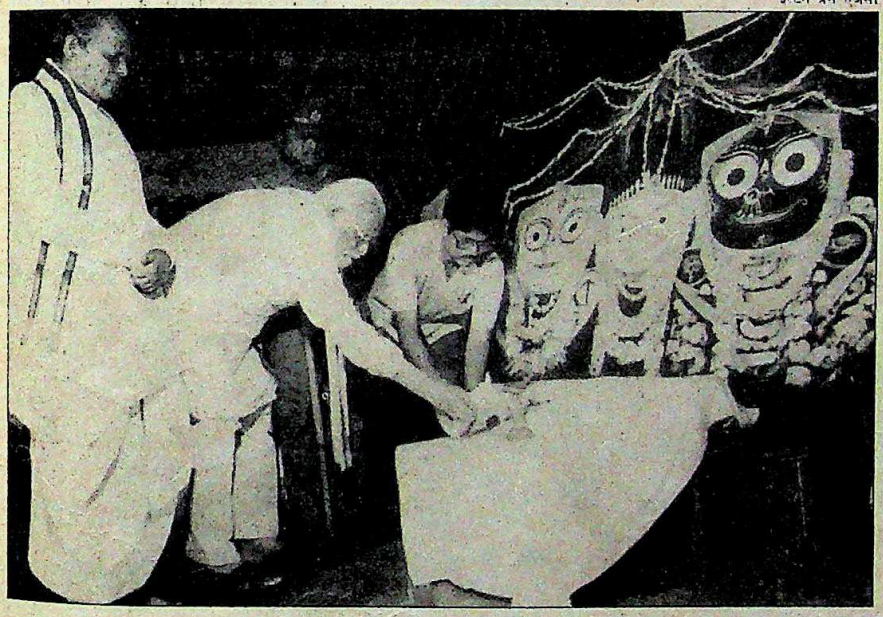

(बाएं से) जानकीबल्लभ पटनायक, राज्यपाल बी.एन. पांडे और सोमैया रंजन: बुलंद सितारा

इस फैसले के बाद ही सोमैया रंजन को बस मालिक संघ का अध्यक्ष बना दिया गया. पर संपादक का कहना है कि शहर के बस मालिक कोई गैरकानूनी काम नहीं कर रहे.

• सरकार उन ईंट निर्माताओं के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से हिचकिचाती है जो गैरकानूनी तौर पर नदी के किनारों और तटबंधों का इस्तेमाल करते हैं. विधानसभा में जब इस मामले पर हल्ला हुआ तो सोमैया रंजन को ईंट-भट्ठा निर्माता संघ का अध्यक्ष बना दिया गया.

इन सब आरोपों के बावजूद या शायद उन्हीं की बदौलत सोमैया रंजन की छत्र-छाया में पल रहे संगठनों की सूची बढ़ती ही जा रही है. पर सोमैया रंजन के आलोचक संपादन के क्षेत्र से हटकर की गई उनकी हरकतों से ही नहीं भड़के. अखबार का उनका साम्राज्य भी आलोचकों का निशाना है. पांच साल पहले जब सोमैया रंजन ईस्टर्न मीडिया लि. नामक कंपनी लेकर मैदान में उतरे तो मुख्यमंत्री हर तरफ से आरोपों की बौछार में फंसे थे. सरकार ने इस धंधे के लिए 90 लाख रु. कर्ज और भुवनेश्वर के एक रिहायशी इलाके में तीन एकड़ बढ़िया जमीन देने में बहुत फुर्ती दिखाई.

सोमैया रंजन कहते हैं कि वे शिक्षण के पेश से उकता गए थे और ऐसा ठौर तलाश रहे थे जहां अपना 'रंग' जमा सकें. 'संवाद' उनकी इसी खोज का नतीजा था.

वहीं से सोमैया रंजन चमत्कारी बुलंदियां चढ़ते गए. उन्होंने 'कथा' (लघु कहानी पत्रिका) शुरू की, फिर 'सिने संवाद' (फिल्मी पत्रिका) और 'सहारा' (उर्दू की समाचार पत्रिका) निकाली. सरकारी विज्ञापन अखबार के लिए कोई समस्या नहीं रहे हैं. दो ही महीने पहले उन्होंने अंग्रेजी दैनिक 'सन टाइम्स' शुरू किया.

सोमैया रंजन ने दूसरे अखबार खरीदने के लिए भी पैसा झोंक दिया. हालांकि दैनिक 'जनभाषा' खरीदने की उनकी कोशिश सिरे नहीं चढ़ सकी पर वे दैनिक 'खबर कागज' और लोकप्रिय ओडिया साप्ताहिक 'ट्यूजडे' को अपने साम्राज्य में शामिल करने में कामयाब हो गए.

सोमैया रंजन ने जिस तेजी से अपनी हैसियत बनाई है, उसे देखते हुए हैरानगी नहीं कि ओडीसा की राजनीति में उनका सितारा और तेजी से चमकने लगे.

—फरजंद अहमद, भुवनेश्वर में

ओडीसा

महंगा मेला

किसानों को लुभाने की कसरत

यह किसानों का अपूर्व मेला था. पहले किसी राज्य में ऐसा मेला देखने में नहीं आया. पिछले महीने ओडीसा की 4,500 पंचायतों में से करीब 60,000 किसानों को एक सम्मेलन में भाग लेने और अपनी शिकायतें सरकार के सामने रखने के लिए सरकारी खर्च पर राजधानी भुवनेश्वर लाया गया. और इतनी बड़ी भीड़ जुटाने पर लागत 'महज' तीन करोड़ रुपए आई.

इस फिजूलखर्ची की आलोचना होना स्वाभाविक था. सत्ताधारी इंका के लोग भी इसमें पीछे नहीं रहे. नाम प्रकाशित न करने की शर्त पर पार्टी के एक विधायक ने कहा, "यह सरकारी मशीनरी और खजाने का सरासर दुरुपयोग है."

लेकिन मुख्यमंत्री जानकीबल्लभ पटनायक, जो प्रदेश इंका अध्यक्ष कालीचरण लेंका के विरोध के बावजूद इस आयोजन के सूत्रधार रहे, इसे 'कामयाब कसरत' करार देते हुए कहते हैं, "सभी राजनैतिक पार्टियां किसानों को गुमराह कर रही हैं. इसीलिए सरकार ने सभी पंचायतों से किसान प्रतिनिधि बुलाकर उनकी समस्याएं सुनने और कोई हल तलाशने का फैसला किया."

इसके लिए किसानों को 500 से ज्यादा बसों और रेलगाड़ियों में भरकर भुवनेश्वर लाया गया. मुख्य सचिव एन.के. पांडा ने सम्मेलन की अध्यक्षता की जबकि कृषिमंत्री रासबिहारी बेहेरा को बतौर 'सम्मानित अतिथि' संतुष्ट होना पड़ा. कुछ वाद-विवाद और समूह चर्चाएं भी चलीं पर कुल मिलाकर मेला एक तमाशा ही रहा. इस मेले की मुख्य बातें हैं:

► ग्रामीण क्षेत्रों में उर्वरक की एक हजार और अनुदानित दुकानें खोलना.

► 80,000 वनवासियों और छोटे किसानों की सहकारी कर्ज से मुक्ति के लिए कर्जदाता संस्थाओं को गरीबी हटाओ कार्यक्रम के कोष से दो करोड़ रु. मुआवजा देना.

► 50,000 कुएं खुदवाने के लिए भारी अनुदान देना.

► पंचायत स्तर पर 1.2 लाख किसानों के लिए फसल बीमा योजनाएं लागू करना

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

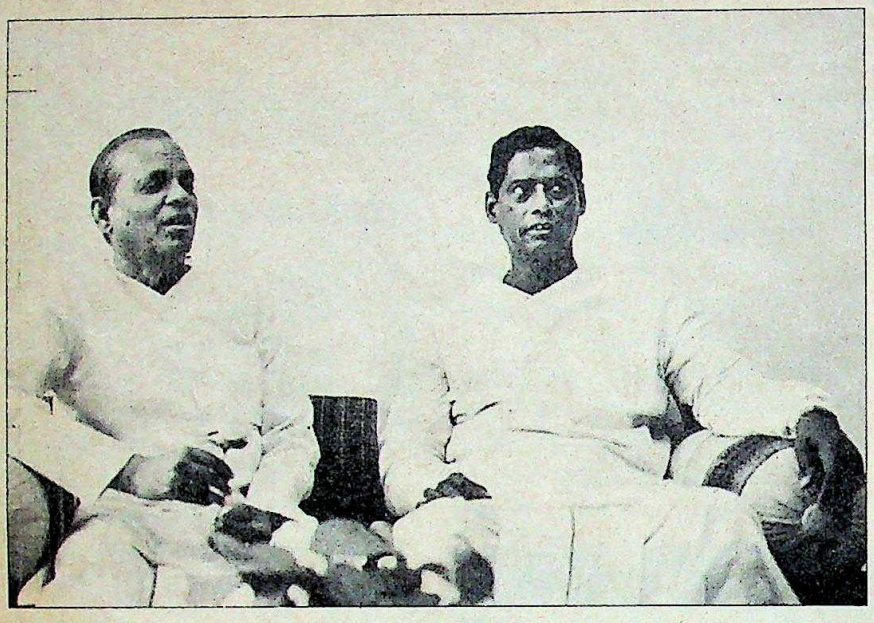

पटनायक (बाएं) प्रदेश
इंका अध्यक्ष लेंका के साथ

(इस पर 18 करोड़ रु. लागत आएगी, छह करोड़ राज्य सरकार देगी तथा बाकी केंद्र और बीमा कंपनियां).

पर बहुत से विपक्षी नेता मानते हैं कि इस मेले ने एक ही बात साबित की है कि इंका ग्रामीण मतदाताओं पर पकड़ बहाल करने की जीतोड़ कोशिश कर रही है.

इस बात में दम भी है. सूखे ने किसानों को खस्ताहाल कर दिया है. राहत कार्य भी अपर्याप्त रहे हैं. इससे विपक्ष को आगामी चुनाव के लिए अपना आधार मजबूत करने का एक बड़ा मुद्दा मिल गया है.

इंका के लिए चिंता की एक और वजह एक स्वतंत्र संगठन ओडीसा कृषक महासंघ है जिसने कुछ जिलों में किसान आंदोलन खड़ा करने में सफलता पाई है. मसलन बोलनगीर जिले में किसानों ने पिछले साल सितंबर में आंदोलन शुरू किया. निर्दलीय विधायक बालगोपाल मिश्र के अनुसार करीब 1,200 किसानों ने अरसे से चले आ रहे सूखे का स्थायी हल ढूंढ़ने की मांग करते हुए गिरफ्तारियां दी.

लेकिन धेनकानाल जिले के अथमलिक उपमंडल में कृषक की अगुआई वाले किसान आंदोलन ने तो सचमुच अधिकारियों की नींद हराम कर दी. इस साल फरवरी-मार्च में 3,000 से भी ज्यादा किसानों और उनके परिवारवालों ने गिरफ्तारियां दीं. वे अपने जिले में अरसे से लटकी आ रही माजोर सिंचाई परियोजना पर अमल करने की मांग कर रहे थ. यह ओडीसा का पहला प्रमुख किसान आंदोलन था जिसे न केवल विपक्ष बल्कि कुछ स्थानीय इंका विधायकों और सांसद के.पी. सिंहदेव का भी समर्थन हासिल था. जब सरकार ने उनकी मांगें मान लीं तो किसान राज्य में दूसरी जगहों पर भी आंदोलन करने को प्रेरित हुए.

दरअसल तीन महीने पहले लेंका को प्रदेश पार्टी अध्यक्ष बनाया जाना किसानों में फैले असंतोष का ही नतीजा था. उनके इस पद पर आने से पहले असंतुष्ट इंका नेताओं तक ने पटनायक सरकार के खिलाफ किसानों को संगठित करना शुरू कर दिया था. उन्होंने कटक, कोरापुट और गंजाम जिलों में किसान सम्मेलन किए. पर इससे पहले कि लेंका कोई कदम उठाते मुख्यमंत्री ने फिजूलखर्ची मेले का आयोजन कर डाला.

लेकिन सारी कसरत 1980 में पटनायक के सत्ता में आने के बाद ग्रामीण क्षेत्र में सरकार की नाकामियों पर शायद ही परदा डाल पाए. इस अरसे में कोई भी प्रमुख सिंचाई योजना शुरू नहीं की गई, हालांकि सरकार बार-बार वायदे करती आई है कि वह राज्य के 314 ब्लाकों में से हरेक में 1,000 एकड़ भूमि सिंचाई के तहत लाएगी. मसलन सुंदरगढ़ जिले में 40 फीसदी खेतों को 1990 तक सिंचाई के तहत लाने का वायदा किया गया, पर अभी तक चार फीसदी इलाके को ही पानी मिल पाया है. सच बात तो यह है कि हीराकुंड बांध के तहत आने वाले क्षेत्र को छोड़कर राज्य के कृषि उत्पादन में गिरावट ही आई है.

ऐसे में अगर मुख्यमंत्री हाल ही के मेले का राजनैतिक लाभ उठाने में नाकाम रहे हैं तो इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं.

—फरजंद अहमद, भुवनेश्वर में

मिजोरम

सपना और संकट

वृहत्तर मिजो राज्य की मांग

भारत-बर्मा सीमा पहाड़ी पर पिछले महीने तीन देशों के करीब 2,700 मिजो इकट्ठा हुए थे और उन्होंने मिलजुलकर एक सपना देखा था. वह सपना था तीन देशों से थोड़े-थोड़े हिस्से निकालकर उनके कबीले के लिए एक राज्य के निर्माण का. इस 'काल्पनिक' राज्य में मिजोरम का खूबसूरत नगर चंपाई, बर्मा की चिन पहाड़ियां, बांग्लादेश के चिटगांव के पहाड़ी इलाके, मणिपुर का चूड़ाचांदपुर और त्रिपुरा की जंपुई पहाड़ियां शामिल हैं. यदि ये सभी इलाके मिजोरम में मिला दिए जाएं तो उसका क्षेत्रफल 21,087 वर्ग किमी से बढ़-

सैलो: लोकप्रिय चाल

नक्शा: बी.के. शर्मा

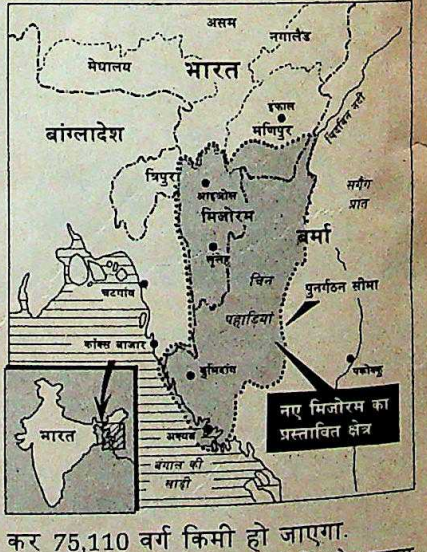

कर 75,110 वर्ग किमी हो जाएगा.

मिजोरम के पांच लाख लोगों और राज्य के बाहर रहने वाले दूसरे 20 लाख मिजो लोगों के लिए यह सपना बुना था पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स कान्फ्रेंस के अध्यक्ष 66 वर्षीय ब्रिगेडियर थेनफुंगा सैलो ने. यह सम्मेलन उन्होंने ही बुलाया था. उनके उत्साह से प्रेरणा लेकर लगभग 200 प्रतिनिधियों ने जैतूनी रंग की वर्दी में 28 मई को एकीकरण के नारे लगाते हुए आइजोल तक 200 किमी. का मार्च किया.

इससे यह बिलकुल साफ हो गया कि सैलो की इस चाल का मकसद मुख्यमंत्री

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

अब शक्ति आपके हाथ

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

HONDA

बार बार बिजली जाने से परेशान हैं? बेफ़िक्र रहें। श्रीराम होन्डा पोर्टेबल जेनसेट की शक्ति अब आपके हाथ है। आप अपने घर में आराम, दफ्तर में काम और दुकानों में बिक्री पूरी बेफ़िक्री से कर सकते हैं।

होन्डा—दुनिया के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक पोर्टेबल जेनसेट्स के निर्माता—की ताकत अब आपकी ताकत है। होन्डा जेनसेट्स भारत के लिए नए नहीं हैं— 100,000 से भी ज्यादा होन्डा जेनसेट्स आज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। विदेश से आयात किए गए हर पाँच में से चार जेनसेट्स 'होन्डा' ही हैं।

अब श्रीराम और होन्डा का संयुक्त सहयोग आपके लिए होन्डा के दो भारत में प्रमाणित मॉडल्स लाया है। हर मॉडल ईंधन की बचत करने वाला, बिना आवाज़ काम करने वाला, हल्का, भरोसेमंद, और सुरक्षित है। श्रीराम होन्डा का हर जेनसेट स्थिर वोल्टेज देता है। श्रीराम होन्डा के हर जेनसेट के पीछे है होन्डा की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की ख्यातिप्राप्त सर्विस। अधिक जानकारी और मुफ्त प्रदर्शन के लिए संपर्क करें—श्रीराम होन्डा के 80 से भी अधिक डीलर्स में से-किसी एक से।

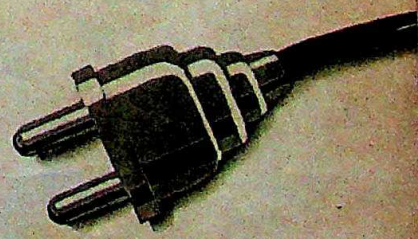

SHRIRAM HONDA
PORTABLE GENSETS

श्रीराम होन्डा पॉवर इक्विपमेन्ट लिमिटेड
ईलीमहल, 19 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
फोन: 5739103, 5723528.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हवाओं में एक नई

Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ओं में
क नई महकती
हलचल!

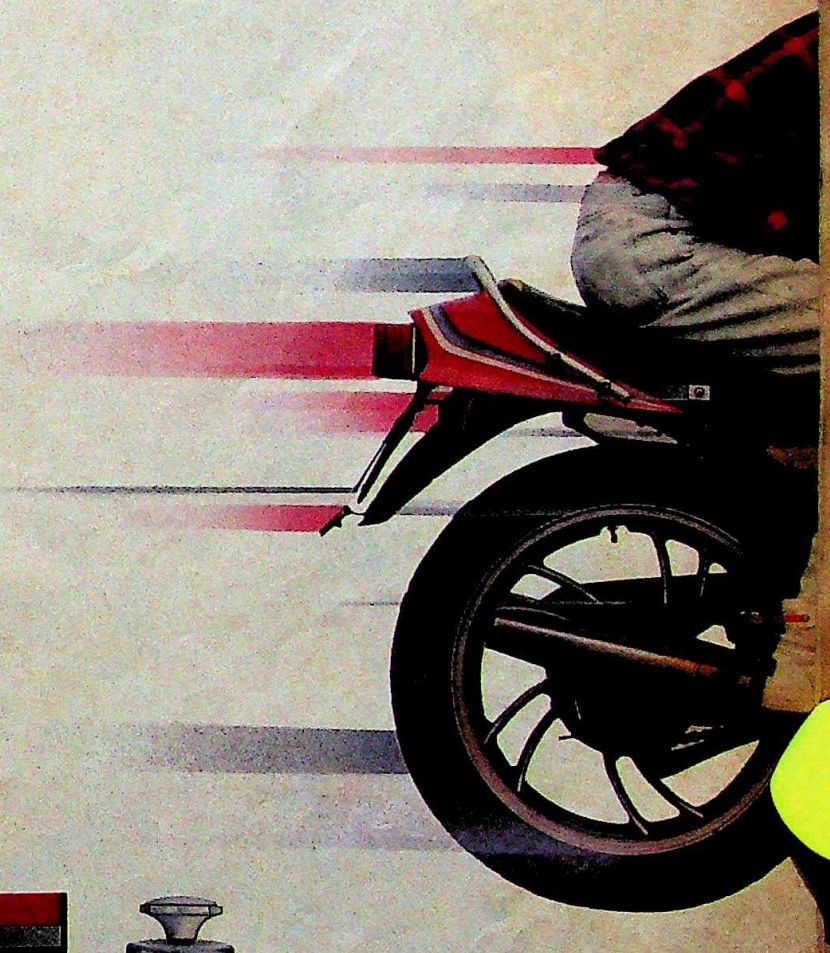

सनसनाती! महकाती! ठंडक और ताज़गी बरसाती
मदमाती हलचल! ओल्ड स्पाइस आफ़्टर शेव
लोशन के साथ.

सुगंध, जो देर तक आप से लिपटी रहे...
आप का सुगंधित परिचय बन जाए!
शेव के बाद... स्नान के बाद... किसी ख़ास बात से
पहले... किसी मुलाकात से पहले, ओल्ड स्पाइस

मि. ली. के पैक में. केवल १८.००* रु.

* स्थानीय कर अलग

ओल्ड स्पाइस
मर्दानगी की मस्तानी महक
मैनेज़ीज़ शुल्टन का एक उत्कृष्ट उत्पादन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

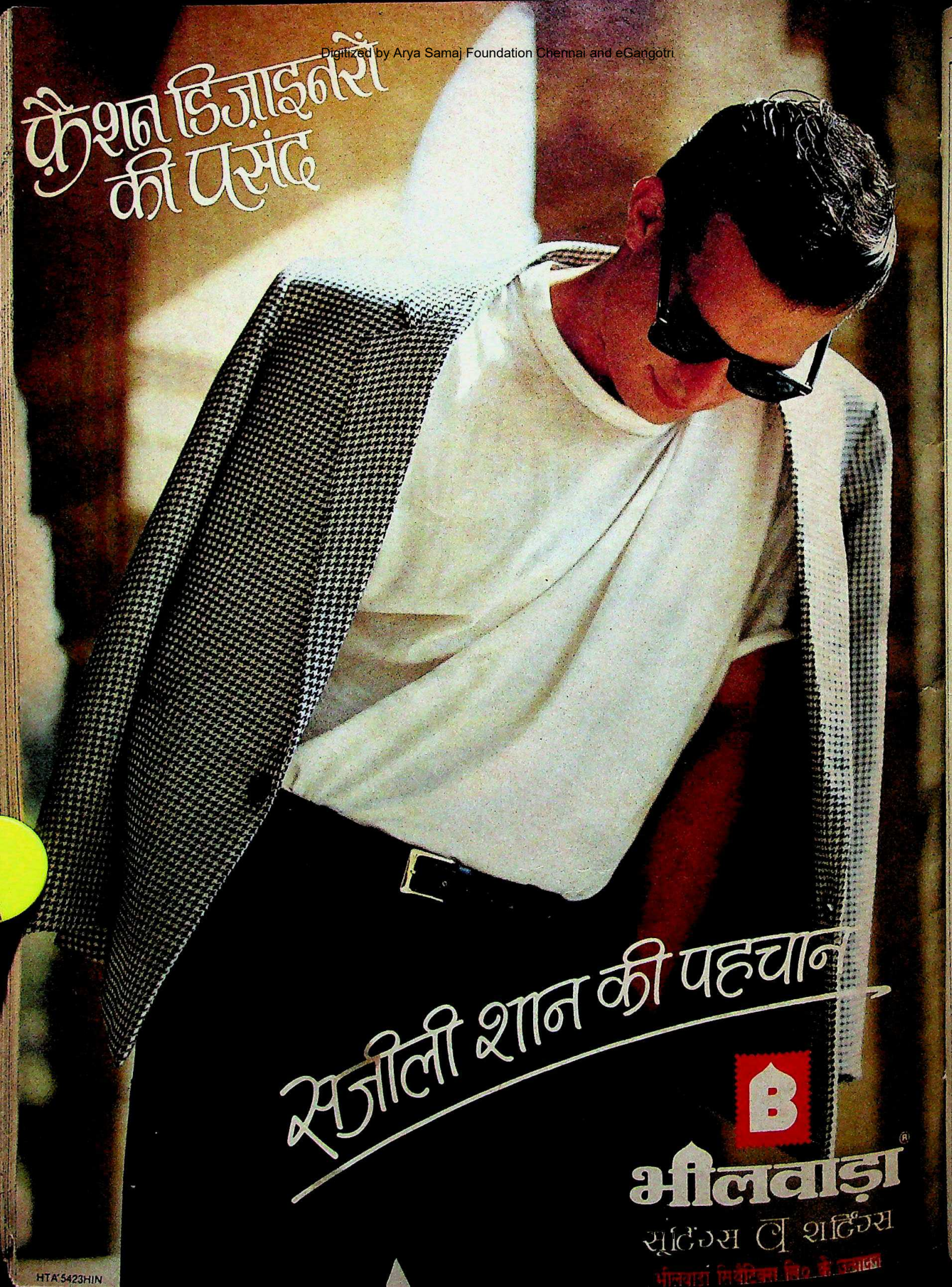

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ललदेंगा के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट को मात देना है. मिजोरम की 40 सदस्यीय विधानसभा में पीपुल्स कान्फ्रेंस के सिर्फ दो सदस्य हैं. लिहाजा, उसे जनसमर्थन की सख्त जरूरत है. और एकीकरण का सपना ही वह चीज है जिससे लोगों को लुभाया जा सकता है.

इस बीच ललदेंगा बड़ी पेचीदा स्थिति में फंस गए हैं. अगर वे सैलो का विरोध करते हैं तो उनकी लोकप्रियता घटने का खतरा है और अगर उनका समर्थन करते हैं तो सैलो की ही स्थिति मजबूत होगी. और तो और, खुद ललदेंगा ने भी शुरू में 'वृहत्तर मिजोरम' की बात कही थी. लेकिन इसमें भारत के बाहर के इलाके शामिल नहीं थे.

सैलो के आह्वान का सीमा पार के इलाकों में व्यापक स्वागत हुआ है. चटगांव के पहाड़ी इलाके और चिन पहाड़ियां भारतीय राज्य के मुकाबले बहुत ही कम विकसित हैं और यहां रहने वाले मिजो लोगों का विश्वास है कि वे मिजोरम में बेहतर जीवन जी सकते हैं. सम्मेलन में एक बांग्लादेशी मिजो एल. सन्नगम ने भी भाग लिया था. वे बांग्लादेश से अलग होने की मांग करने वाले चटगांव हिल ट्रैक्ट्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं. उनका दावा है कि बांग्लादेश में उनके लगभग 3,000 लोग हैं और वे सभी भारत के साथ रहना चाहते हैं.

सैलो के नेतृत्व वाले मिजो लोग एक तरफ जहां चंपाई में अपनी रणनीति बना रहे थे, वहीं दूसरी ओर उनकी रणनीति की काट भी तैयार की जा रही थी. ललदेंगा ने बर्मा के लोगों को प्रवेश पत्र देना अस्थायी रूप से रुकवा दिया और सरकारी कर्मचारियों को चेतावनी दी कि यदि उन्होंने सैलो के संगठन 'जो रियुनिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन' को चंदा दिया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

सैलो को भी सम्मेलन से निराशा ही हुई. उन्होंने उम्मीद की थी कि सम्मेलन में सैकड़ों विदेशी प्रतिनिधि भाग लेंगे लेकिन आए केवल 60 लोग—बांग्लादेश से 50 और बर्मा से 10. जब सैलो ने कहा कि उन्हें केंद्र का समर्थन हासिल है तो ललदेंगा ने उसकी जांच-पड़ताल की. इस पर नई दिल्ली का जवाब था कि उसने आंदोलन का समर्थन नहीं किया है.

यदि केंद्र का यह कहना सही है तो यह फैसला बुद्धिमानीपूर्ण है. सैलो के आंदोलन के प्रति उदासीनता दिखाकर ही उसे खत्म किया जा सकता है.

—रमेश मेनन, आइजोल में.

शराब नीति

चर्च का असर

लोग ठगे-से रह गए. मिजोरम के मुख्यमंत्री ललदेंगा ने अचानक फैसला सुना दिया कि मार्च में राज्य की शराब की फुटकर दुकानों के लाइसेंसों की अवधि खत्म होने के बाद उनका नवीनीकरण नहीं किया जाएगा. राज्य में यहां हर महीने देसी शराब की 1.2 लाख से भी अधिक बोतलों की खपत होती है. मिजो राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के इस फैसले से शराब के दाम अचानक ही आसमान छूने लगे और अवैध शराब के धंधे के साथ जमाखोरी भी बढ़ गई.

शराब के व्यापारियों से फरवरी में ही कह दिया गया था कि वह उतनी ही शराब रखें जो मार्च के आखिर तक बिक जाए. इसी के बाद उन्होंने मशहूर ब्रांडों की शराब की जमाखोरी शुरू कर दी. अब उनका धंधा खूब जोरों पर है. अमूमन 39 रुपए वाली 'हरकुलस' रम 120 रु. में बिक रही है, 48 रु. वाली हनी बी ब्रांडी की कीमत 180 रु. पर पहुंच गई है, 14 रु. वाली ब्लैक लेबल बियर का दाम है 40 रुपए.

आबकारी विभाग ने अकेले आइजोल में ही अवैध शराब बनाने और बेचने के 120 मामले दर्ज किए हैं. आबकारी के उपायुक्त आर. ललजाउआ मानते हैं कि "अवैध शराब की बिक्री बढ़ी है".

खुद ललदेंगा भी शराबबंदी के हक में नहीं दिखते क्योंकि 'नाजायज शराब पर रोक लगाना नामुमकिन है'. लगता है उनकी यह कार्रवाई शराब और मादक दवाओं के खिलाफ चर्च द्वारा छेड़े गए जोरदार अभियान के असर में की गई है.

पिछले दो साल से प्रेस्बीटरी चर्च शराब के परमिट खत्म करने के लिए दबाव डाल रहा था. ललदेंगा चर्च को नजरअंदाज करने की जहमत मोल नहीं ले सकते क्योंकि इस ईसाईबहुल राज्य में उसका गहरा प्रभाव है. आइजोल में प्रेस्बीटरी चर्च के कार्यकारी सचिव ललसावमा कहते हैं, "हम पीने के खिलाफ नहीं हैं. हमें चिंता इस बात की है कि यह एक व्यापक मर्ज बनता जा रहा है और समाज पर असर डाल रहा है."

प्रशांत गजियार

गोदाम में शराब के कार्टन: जमाखोरी

मिजोरम के 226.37 करोड़ रु. के कुल बजट में करीब 93 फीसदी तो केंद्र से मिली सहायता शामिल रहती है. राज्य द्वारा खुद उगाहे जा रहे 3.5 करोड़ रु. की करों में से शराब पर आबकारी शुल्क के खाते में ही 2.95 करोड़ रु. आते हैं. राज्य सरकार के अधिकारियों का तर्क है कि परमिट का नवीनीकरण न करने से वित्तीय तबाही आ जाएगी.

पर ललदेंगा अभी भी यही कहते हैं कि लाइसेंस नवीनीकरण के मामले में आखिरी फैसला बाकी है. उन्हें उम्मीद है कि कुछ समय टालमटोल के बाद वे चर्च को इस भरोसे राजी कर लेंगे कि वे समस्या का गहराई से अध्ययन कर रहे हैं. उधर इंका नेताओं का कहना है कि वे जल्द ही दुबारा लाइसेंस तो जारी करेंगे पर अब पुराने लाइसेंसधारियों को नहीं देंगे क्योंकि उनमें ज्यादातर इंका समर्थक हैं. इंका के संयुक्त सचिव ए.आर. मल्लू कहते हैं, "नए लाइसेंस दूसरे लोगों को नहीं बल्कि मिजो नेशनल फ्रंट के समर्थकों को ही मिलेंगे."

इस आरोप की सचाई तो तभी उजागर होगी जब अगले महीने लाइसेंस नवीनीकरण पर फैसला होगा.

—रमेश मेनन, आइजोल में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बरखास्तगी वजीरे आजम की

लोग सुनकर हैरत में रह गए. उस दिन सुबह अखबारों में खबर छपी कि सदर जिया उल हक ने यकायक ही पाकिस्तान की कौमी असेंबली को भंग करके अपने वजीरे आजम को बरखास्त कर दिया है और 90 दिनों के अंदर ताजा चुनाव कराने का एलान कर दिया है. सारा काम ऐसे गुपचुप तरीके से हुआ कि वजीरे आजम जुनेजो को भी इसकी भनक न मिली. उन्हें यह बात अखबारनवीसों से ही पता चली. कुदरती तौर पर दुनिया भर के लोग तफसील जानने को उत्सुक थे कि आखिर यह सब क्यों और कैसे हुआ? हमने छानबीन के लिए फौरन अपने खोजी संवाददाताओं को रवाना किया. पेश है तफतीश के बाद उनकी रिपोर्ट:

लगता है एक रोज वजीरे आजम जुनेजो जनरल जिया से मिलने गए और मुलाकात के दौरान उन्होंने जिया से कहा, "जनरल साहिब, मुझे यह कहते हुए शर्मिंदगी का एहसास तो होता है पर मैं आप पर हुक्म नहीं चलाना चाहता. फिर भी अगर आप अपने ओहदे से इस्तीफा दे दें तो कैसा रहे? मेरा ख्याल है कि अब फौज का कोई नया ही कमांडर इन चीफ होना चाहिए."

जनरल जिया अपने होंठ चबाकर रह गए. कुछ बोले नहीं. वजीरे आजम के लौटते ही वे भागकर सदर जिया के पास पहुंचे और बोले, "बॉस! जुनेजो मुझे सेना के ओहदे से हटाना चाहता है. उसे फिक्र इस बात की है कि मैं आपके बहुत करीब हो गया हूं."

सदर जिया भन्ना गए और बोले, "क्या, सचमुच? जुनेजो इतना फिक्रमंद कैसे हो गया? मैं ऐसे बहुत सारे फौजी कमांडरों को जानता हूं जिनका अपने मुल्क के सदर से करीबी ताल्लुक है."

"बॉस! मुझे लगता है कि जुनेजो किसी और बात पर खफा है. दरअसल आप इस्लामी रियासत जो बना रहे हैं," मौलाना जिया बोले. वे भी पास ही खड़े थे, "और आपके वजीरे आजम इस्लामी पाकिस्तान बनाना नहीं चाहते."

"पर जुनेजो इस्लामी पाकिस्तान बनाए जाने के खिलाफ क्यों है?" सदर जिया ने कैफियत तलब की.

फौरन ही जंगे आजादी के सिपहसालार जिया बीच में टपक पड़े और कहने लगे, "क्योंकि उसका मानना है कि अगर पाकिस्तान इस्लामी न हो तो हम अफगानिस्तान के साथ अमन-चैन से रह सकते हैं. हकीकत यह है बॉस कि आपके वजीरे आजम को मुजाहिदीनों की सरगर्मियां पसंद नहीं."

"या खुदा! उनकी मुखालफत किस बात पर?" सदर जिया ने पूछा

"बॉस! वजह यह है कि बहुत से लोग अफगानिस्तान की जंग के दौरान आए मुजाहिरों को सरकारी ढांचा चरमरा जाने का सबब मानते हैं. सूबाई सरकारें बेअसर हो गई हैं," शहरी जिया बोले.

"तो ऐसी सूरत में हमें मरकजी और सूबाई असेंबलियां तोड़ देनी चाहिए," सदर जिया ने फरमाया, "पर मुझे डर है लोग कहीं यह न सोच लें कि मैं जम्हूरियत के खिलाफ हूं या मुल्क में मार्शल लॉ बहाल करना चाहता हूं."

"ऐसा कोई नहीं बोल सकता, बॉस!" वकील जिया ने दलील दी. अभी तक वे संजीदगी से सुनते ही आ रहे थे. "जब तक मरकजी कौंसिल कायम रहेगी, कोई भी यह कहने की जुर्रत नहीं कर सकता कि जम्हूरियत खत्म हो गई है."

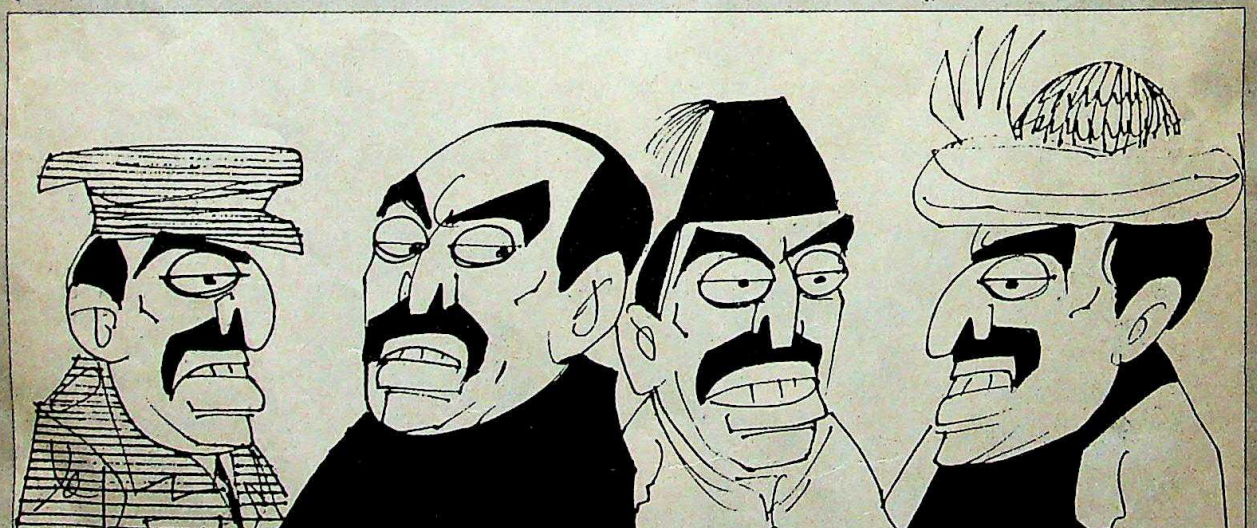

"तो ठीक है. हर कोई मशविरा दे कि मैं क्या करूं?" सदर जिया ने पूछा.

"असेंबलियां तोड़कर जुनेजो को बरखास्त कर दें और ताजा चुनाव कराने का हुक्म दें, बॉस!" हर किसी ने एक ही आवाज में यह राय दी.

सदर जिया आह भरे उठे. गमगीन होकर उन्होंने कहा, "मुझे जुनेजो से कोई गिला नहीं है. वह निहायत शरीफ आदमी है. पर पाकिस्तान में जब हर कोई सरकार की बरखास्तगी चाहता है तो मैं बीच में कैसे आऊं?..."

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

फेरीवालों के फेर में

भाजपा के नेतृत्व वाले अहमदाबाद नगर निगम और राज्य की इंका सरकार के बीच ठन गई है. पिछले महीने भाजपा पार्षदों ने महापौर जयेंद्र पंडित की अगुआई में सरकारी दखलंदाजी के खिलाफ 72 घंटे की भूख हड़ताल की.

नगर निगम ने 3,000 फेरीवालों को हटने के लिए आठ दिन का नोटिस दिया था, लेकिन इस पर कार्रवाई होने से पहले ही सरकार ने निगमायुक्त एन.एम. बिजलानी को एक चिट्ठी भेजकर

भूख हड़ताल पर भाजपा के विधायक: पक्का इरादा

कहा कि फेरीवालों को हटाने से पहले वैकल्पिक व्यवस्था की जाए. चिट्ठी में कहा गया कि इस बारे में सलाह सरकार से भी ली जाए.

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शंकरसिंह वघेला ने कहा, "सत्तारूढ़ पार्टी इस मुद्दे से राजनैतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है." विरोध में पार्टी ने तत्काल अहमदाबाद बंद का आह्वान किया.

जवाब में सत्तारूढ़ पार्टी ने भी भाकपा के सहयोग से फेरीवालों के समर्थन में प्रदर्शन किए. लेकिन बंद सफल रहा. बहरहाल फेरीवालों को हटाने का अभियान अभी शुरू नहीं हो पाया है, लेकिन, निगम का दावा है कि वह जल्दी ही इस अभियान को चलाएगा.

आग से मिला नया अनुभव

आग से खेलना नेताओं का काम तो है. लेकिन पिछले पखवाड़े लखनऊ में बीरबहादुर सिंह के बंगले में आग लगने से वे सचमुच इस स्थिति में आ गए. कमरों से उठती लपटों की तरफ एकटक देखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "मैंने जो कुरता-पायजामा पहन रखा है, इसे छोड़ मेरे पास कुछ नहीं बचा है."

यह विडंबना ही है कि आग उसी दिन लगी जिस दिन राज्य के दमकल विभाग ने आग पर काबू पाने के उपाय तलाशने के लिए उच्च-स्तरीय बैठक की बैठक के तुरंत बाद दमकल विभाग की सतर्कता की परीक्षा की घड़ी आ गई और उसने हाल ही में प्राप्त

सिंह के घर का जला हुआ हिस्सा

क्रेन लैडर (सीढ़ी) उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री के बंगले की ओर रवाना किया. जिस समय आग लगी बीरबहादुर कहीं गए हुए थे. उनके कमरे में लगा एअर-कंडीशनर चालू था और उसमें किसी तरह की खराबी के कारण आग लग गई. दरवाजा बाहर से बंद होने के कारण आग लगने की जानकारी रात आठ बजे ही मिल पाई.

उस रात उनके परिवार के लोग बरामदे में फोल्डिंग चारपाइयों पर सोए. सवेरे मुख्यमंत्री ने मच्छरों के काटने की शिकायत करते हुए कहा, "अब मैं जान पाया हूं कि जिन गरीब ग्रामीणों का आग में सब कुछ स्वाहा हो जाता है, उन पर क्या बीतती है."

राज्य सरकार आग लगने के मामले में 50 रु. की खैरात देती है, लिहाजा विपक्ष ने इतनी कम रकम की तरफ सरकार का ध्यान खींचने के लिए उस घटना को उछाला. लोकदल के महासचिव जनेश्वर मिश्र ने तुरंत एक प्रेस कान्फ्रेंस बुलाकर घोषणा की कि वे 50 रु. इकट्ठा करके मनीऑर्डर द्वारा बीरबहादुर को भेजेंगे.

छोटे परदे का मोह

सिक्किम के नरबहादुर भंडारी शायद एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो टेलीविजन के परदे पर प्रधानमंत्री राजीव गांधी जितनी ही जगह पाते हैं. दूरदर्शन पर पक्षपात करने का आरोप लगाने के बजाय उन्होंने छोटे परदे पर आने का एक नायाब नुस्खा ढूंढ़ निकाला है. उन्होंने सिक्किम संग्राम परिषद के मुख्यालय और अपने कट्टर समर्थकों के घरों में केबल टीवी का नेटवर्क बिछा रखा है.

परिषद का केबल टीवी अप्रैल से गंगटोक, जोरथांग और सिमथांग के लोगों को पश्चिम की ताजा फिल्मों, रॉक संगीत और पॉप शो से मनोरंजन करता आ रहा है. ग्राहकों ने केबल टीवी अपने घरों में लगवाने के लिए 1,000 रुपए दिए हैं. बताया जाता है कि परिषद भी इससे फायदे में है और खूब पैसे बटोर रही है.

भंडारी: धूमिल इरादे

सब कुछ ठीकठाक चल रहा था कि अचानक दिल्ली तक इसकी खबर पहुंची. सूचना और प्रसारण सचिव गोपी अरोड़ा ने तत्काल संचार मंत्रालय को निर्देश दिया कि इन कार्यक्रमों पर रोक लगाई जाए. उन्होंने इसे 'एक ऐसा सांस्कृतिक हमला' करार दिया 'जिसके लिए सरकार अनुमति नहीं देगी.'

घोषणाओं के शौकीन

अर्जुन सिंह घोषणाएं करने के शौकीन हैं. मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्रित्व के अपने पहले 100 दिनों में उन्होंने हर चौथे दिन एक 'महत्वपूर्ण' घोषणा गरीब और बेघरों के लिए की है. राज्य के जनसंपर्क विभाग ने अब अर्जुन सिंह की 'सफल शताब्दी' के दौरान की उपलब्धियों का एक मोटा पोथा भी प्रकाशित कर डाला है.

लेकिन मुख्यमंत्री के प्रचारकों को जितनी उम्मीद थी, इन सभी घोषणाओं को उतना प्रचार नहीं मिला. क्षेत्रीय अखबारों ने तो जैसे-तैसे कर्तव्य निबाहा. लेकिन राष्ट्रीय अखबारों ने अमूमन इनकी अनदेखी कर दी. वजह यह है कि अर्जुन सिंह के प्रथम मुख्यमंत्रित्व काल (1980-1985) के दौरान घोषित सैकड़ों योजनाओं में से ज्यादातर अभी तक अधूरी पड़ी हैं.

ज्यादा ताज्जुब तो यह है कि दूरदर्शन ने भी इनकी अनदेखी की. इसके पीछे कहीं दूरदर्शन के नियंत्रणकर्ता हरकिशनलाल भगत का हाथ तो नहीं जिन्हें अर्जुन सिंह का करीबी दोस्त नहीं माना जाता.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ब्रह्मचारी फिर संकट में

धीरेंद्र ब्रह्मचारी एक बार फिर संकट में हैं. चार साल पहले जम्मू-कश्मीर पुलिस ने उनकी बंदूक फैक्टरी पर छापा मारा था और अब पिछले पखवाड़े राज्य सरकार ने मानतलाई के उनके अपर्णा आश्रम की जमीन के अधिग्रहण के लिए नोटिस भेज दिया. मानतलाई ऊधमपुर जिले में एक निहायत ही खूबसूरत जगह है. जम्मू-कश्मीर की सरकार पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस जगह पर एक पर्यटक स्थल बनाने पर विचार कर रही है.

मानतलाई आश्रम में ब्रह्मचारी: फिर संकट में

मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को 'उतावला नौजवान' कहने वाले इस योगी ने राज्य सरकार की उक्त नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर दी और स्थगनादेश प्राप्त कर लिया, मजेदार बात तो यह है कि उनके वकील हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री डी.डी. ठाकुर जिनकी फारूक से बनती नहीं है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि "नापाक इरादों से प्रेरित होकर बदला लेने के मसकद से" जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है. ब्रह्मचारी ने फारूक को 'जीवन का तुच्छ भौतिक आनंद खोजने वाला रसिक' तक कह डाला है. इस बीच मुख्यमंत्री लगातार यह कह रहे हैं कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उस जमीन की सख्त जरूरत है.

मुख्य सचिव का पुत्री प्रेम

पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव रथीन सेनगुप्ता विवादों के घेरे में फंस गए हैं. कलकत्ता के अखबारों के अनुसार सेनगुप्ता ने अपनी बेटी पियली की पढ़ाई के मामले में मदद की कथित कोशिश की. पियली अंग्रेजी में मास्टर डिग्री के लिए 1985 में इम्तहान में बैठी थी. लेकिन उसको प्रथम श्रेणी नहीं आया.

नतीजे घोषित होने के तुरंत बाद पियली की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनरीक्षण के लिए आवेदन किया गया. नियमों के मुताबिक यदि कोई छात्र पांच या इससे कम अंकों से प्रथम श्रेणी से वंचित रह जाता है तभी वह पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकता है. लेकिन पियली 7 अंकों से प्रथम श्रेणी से वंचित रह गई थी. विश्व-विद्यालय के सिंडीकेट ने कुलपति भास्कर राय चौधरी के निर्देश पर इसे 15 अप्रैल को अपनी मंजूरी दे दी. हालांकि पियली के लिए नियमों को बड़ी बेशर्मी से तोड़ा-मरोड़ा गया लेकिन सेनगुप्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई. विश्वविद्यालय के अधिकारी इस बात को लेकर परेशान हैं कि ऐसे और आवेदनों का क्या करें.

सजन बोस

सेनगुप्ता

मात दे गए प्रभाकर राव

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नंदमूरि तारक रामराव राज्य के पूर्व वित्तमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल कोणा प्रभाकर राव से मात खा गए. रामराव हैदराबाद के बाहरी इलाके में अगले महीने राष्ट्रीय राजनैतिक चेतना संस्थान शुरू करने वाले थे. लेकिन प्रभाकर राव ने उनसे पहले 6 जून को ही गुंटूर जिले के बापटला में कांग्रेस राजनैतिक प्रशिक्षण संस्थान शुरू कर दिया.

रामराव के संस्थान में जबकि नौ महीने के पाठ्यक्रम होंगे, प्रभाकर राव के संस्थान में मात्र 10 दिन का पाठ्यक्रम है. पूर्व राज्यपाल कहते हैं, "पूर्व और वर्तमान प्रदेश इंका अध्यक्षों और पार्टी विधायकों की सिफारिश वाले 100-100 लोगों के दो जत्थों को हर महीने प्रशिक्षण दिया जाएगा." सफल छात्रों को प्रधानमंत्री जनवरी 1989 में डिग्री देंगे. यहां के पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय आंदोलन, संविधान, केंद्र-राज्य संबंधों, ताजा घटनाओं और लोगों के बीच बोलने की कला पर प्रवचन शामिल है.

बात से बदलेगी बात

रांची में धार्मिक नेताओं के साथ राजीव गांधी की 10 मिनट की बातचीत बिहार की राजनीति का रुख बदल सकती है. पिछले पखवाड़े राजीव गांधी जब रांची गए थे तो उन्होंने शक्तिशाली रोमन कैथोलिक चर्च के आर्कबिशप फादर टी. टोप्पो के नेतृत्व में आए ईसाई नेताओं से बातचीत की. लेकिन मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद को इसमें शरीक नहीं किया गया.

झारखंड राज्य की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन पर इस चर्च का बहुत असर है. सूत्रों के मुताबिक राजीव गांधी और ईसाई नेताओं की बातचीत में आंदोलन, चर्च के प्रति प्रशासन के रवैये, मिशन की समस्याओं, आदिवासियों के उत्पीड़न आदि पर चर्चा हुई. यह बातचीत काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि राजीव ने पहले अलग झारखंड राज्य की मांग नामंजूर कर दी थी.

कृष्ण मुरारी किशन

रांची में राजीव को माला पहनाती ननें: दोस्ती का हाथ

विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन इधर चर्च द्वारा किए जा रहे धर्मांतरणों को रोकने की कोशिश करते रहे हैं. इतना ही नहीं, झारखंड आंदोलन पर चर्च के असर को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने राजीव की यात्रा के ठीक दो हफ्ते पहले तक एक लघु 'वनांचल' राज्य की मांग शुरू कर दी.

कइयों का मानना है कि इस बातचीत का नतीजा इस क्षेत्र में चर्च और इंका के गठबंधन के रूप में निकल सकता है. यदि ऐसा होता है तो इससे झारखंड आंदोलन कमजोर ही होगा. चुनाव के वक्त यह पार्टी के लिए वरदान भी साबित हो सकता है, लेकिन बहुत कुछ स्थानीय प्रशासन, तथा राज्य सरकार के रवैए और इंका नेताओं की भूमिका पर निर्भर करेगा.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

किराया नियंत्रण विधेयक

बड़े लोगों के फायदे में

विवादास्पद संशोधन से कुछ लोग नाराज तो कुछ खुश

कुछ लोगों को यह भीगे पटाखे की तरह लगा तो कुछ ने आधे-अधूरे मन से इसका स्वागत भी किया. पर दिल्ली किराया नियंत्रण कानून में संशोधन के लिए हाल ही में पेश किए गए विधेयक में हर किसी को आलोचना का कोई-न-कोई मुद्दा दिख ही गया. कई वर्षों से इसकी चर्चा और मांग होने से आखिर पिछले महीने बजट अधिवेशन के आखिरी दिन इसे संसद में पेश किया गया. अब मानसून सत्र में इसे बहस के बाद पारित किया जाएगा.

किराया नियंत्रण का मामला राज्यों के अधीन आता है पर केंद्र का मानना है कि यह संशोधन एक राष्ट्रव्यापी मॉडल का काम करेगा. किराया नियंत्रण दूसरे विश्व-युद्ध के समय आपातकालिक उपाय के रूप में शुरू किया गया पर ज्यादातर राज्यों ने 1975 तक इसके बारे में अपने-अपने कानून बना लिए थे. इनमें 1958 का दिल्ली किराया नियंत्रण कानून ज्यादा असंतुलित कानूनों में से एक है.

इस कानून के बारे में दो अलग राय रही हैं. किराएदार इससे खुश थे, तो मकान मालिक इसकी निंदा करते रहे. पर अब नए विधेयक से दोनों पक्षों में कई राय बनेंगी. इससे जहां धनी और अफसर वर्ग के मकान मालिकों को खास तौर पर फायदा होगा, वहीं दूसरे मकान मालिकों को बहुत कम लाभ मिलेगा. उधर किराएदारों को भी इससे कुछ टुकड़े मिल जाएंगे. बहरहाल, मकान मालिकों की लॉबी को निराशा ही हाथ लगी. 'कामन काज' के निदेशक एच.डी. शौरी इसके कुछ प्रावधानों को 'बकवास' मानते हैं. बहुत से मकान मालिकों की तरह उन्हें भी लगता है कि इससे मिलने वाली राहत ढकोसला ही है.

लेकिन महंगे मकानों के मालिकों के तो पौ-बारह हो गए. नए विधेयक के तहत 3500 रु. से ज्यादा किराया देने वाले किराएदारों को पहले का कानूनी संरक्षण अब खत्म हो जाएगा. तर्क यह है कि यदि वे इतना किराया दे सकते हैं तो कहीं और भी आसानी से ठौर तलाश सकते हैं.

ऐसे आवासीय किराएदारों की संख्या कम है पर दक्षिण दिल्ली में वे उतने दुर्लभ भी नहीं हैं. गुलमोहर पार्क जैसी कॉलोनियों में तो तीन बेडरूम के मकान का किराया भी पांच अंकों में पहुंच गया है. और जोरबाग जैसी आलीशान जगह पर चार बेडरूम वाली कोठी के एक लाख रुपए प्रतिमाह तक भी मिल सकते हैं. इसमें ज्यादातर भुगतान काले धन में होता है और कागजों में मात्र 5,000 रु. ही दिखाया जाता है. संशोधन का मकसद यह भी है कि सौदों को खुले में लाया जाए ताकि समांतर अर्थव्यवस्था पर रोक लग सके और ज्यादा स्थानीय कर बटोरने में मदद मिले.

लेकिन व्यावसायिक जगहों के ज्यादातर मालिकों में 3,500 रु. की सीमा ईर्ष्या पैदा करने वाली है. मसलन कनाट प्लेस में पुरानी दुकानें और दफ्तर मात्र 250 से 300 रु. महीने तक किराए पर चढ़े हुए हैं. और कटरा नील में एक कमरे का किराया सिर्फ आठ रु. महीने है, जबकि मकान मालिक का अनुमान है कि कोई व्यापारी इसकी पगड़ी ही छह लाख रु. दे देगा.

विधेयक के मुताबिक किराया नियंत्रक के फैसले के खिलाफ एक ही अपील की जा सकती है और वह भी किसी कानूनी नुक्ते पर. अभी तक ऐसी दो अपीलों की इजाजत थी. विधेयक में आगे से हर तीन साल में 10 फीसदी किराया बढ़ाने का भी प्रस्ताव है. यह इमारतों की बेहतर देखरेख को प्रोत्साहित करने के इरादे से किया गया है. देर से किराया देने पर दंड का भी प्रावधान है. अगर 15 दिन बीतने पर भी किराया नहीं दिया गया तो उस पर 15 फीसदी सालाना की दर से ब्याज देना होगा. दूसरी तरफ कानून में मकान मालिकों के लिए भी कुछ कड़े प्रावधान रखे गए हैं. जो मकान मालिक अपने रहने के लिए किराएदार से मकान खाली करवा लेते हैं, वे अगर तीन साल के अंदर उसे फिर किराए पर चढ़ाते हैं तो उन्हें छह महीने की जेल या जुर्माना देना पड़ सकता है.

पर इसमें कुछ बातों को अस्पष्ट भी रखा गया है. मसलन अगर मुकदमे के दौरान किराएदार की मौत हो जाए तो क्या उसका उत्तराधिकारी मुकदमा आगे चलाए रख सकता है, यह सवाल छोड़ दिया गया है.

ज्यादा विवादास्पद संशोधन वे हैं जिनके तहत सेना के लोगों, केंद्र सरकार और दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों का खास ख्याल रखा गया है. इनमें से जिनके पास अपने मकान हैं वे सेवानिवृत्ति के एक साल पहले या दो साल बाद तक अपने रहने के लिए इसे खाली करवा सकते हैं. सर्व किराएदार संघ के अध्यक्ष एल.एन. मोदी का कहना है कि वे सेना के लोगों के लिए तो यह प्रावधान स्वीकार कर सकते हैं पर प्रशासनिक अधिकारियों के लिए नहीं. उच्चाधिकारियों और नेताओं के लिए ऐसा प्रावधान कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में भी है. वहां भी इसकी खासी आलोचना हुई है. इस पर एक वरिष्ठ अधिकारी व्यंग्य कसते हैं, "आखिर ऐसे कानून यही लोग तो बनाते हैं."

—डेविड देवदास

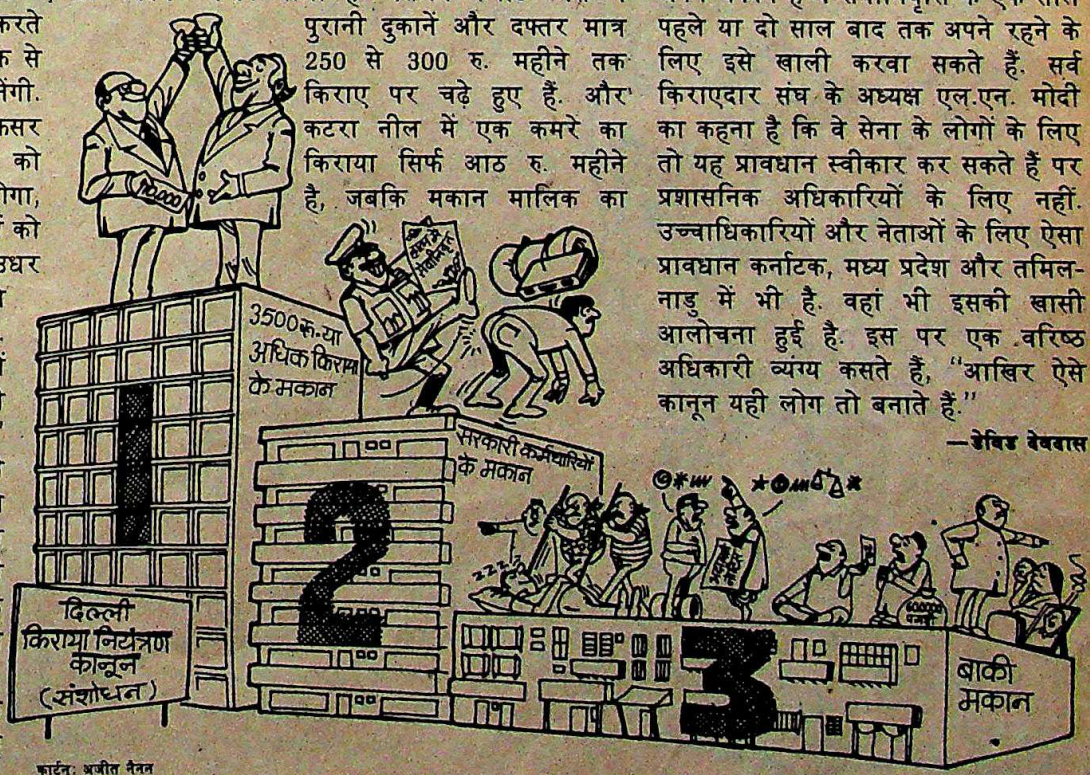

कार्टून: अजीत नैनन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शंकरराव चव्हाण

विदाई की अटकलें थमी नहीं

कांग्रेस आलाकमान के परस्पर विरोधी संकेतों के कारण अनिश्चय

बतौर मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण का हर गुजरता दिन एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि राज्य की राजनीति का हर धुरंधर उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए है. जहां केंद्र सत्ता की इस लड़ाई में असमंजसपूर्ण दर्शक बना हुआ है, वहीं चव्हाण का खेमा भी तैयारी में जुट गया है. इस अखाड़े की रिपोर्ट ब्यूरो प्रमुख ***एम. रहमान*** *की कलम से.*

महाराष्ट्र के 68 वर्षीय मुख्यमंत्री शंकरराव भाउराव चव्हाण की तकदीर भी एक ऐसी अनोखी कहानी है जिस पर कोई दुखांत नाटक तो नहीं मगर शालीन प्रहसन जरूर रचा जा सकता है. मार्च 1986 में जब चव्हाण ने राज्य की बागडोर संभाली थी तो इंका के एक हकबकाए विधायक की टिप्पणी थी, "यह शख्स तो शिवाजीराव पाटील निलंगेकर का भी रिकार्ड तोड़ देगा." निलंगेकर नौ महीने ही मुख्यमंत्री रहे थे. आलाकमान के आदेश पर उनकी जगह चव्हाण ने तो ले ली पर इंका विधायक दल में उन्हें चाहने वाला कोई नहीं था. लगता था कि वे ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे, खासतौर पर इसलिए भी कि पार्टी के बड़े-बड़े धुरंधर उनके नेतृत्व का विरोध कर रहे थे.

चव्हाण राजनीति के मंजे खिलाड़ी साबित हुए. सब लोग हैरत में है कि चव्हाण ने सत्ता में दो साल, तीन महीने कैसे गुजार लिए. फरवरी 1975 में वी.पी. नाइक के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र में किसी मुख्यमंत्री का यह सबसे लंबा कार्यकाल है. पिछले महीने जब इंका महासचिव शीला कौल पार्टी सांसदों व विधायकों से मिलने बंबई पहुंचीं तो राज्य इंका दफ्तर में एक बार फिर अटकलों का दौर चल पड़ा कि चव्हाण अब गए कि तब. लेकिन कौल ने पत्रकारों को बताया कि राज्य नेतृत्व में इतनी जल्दी फेरबदल न तो राज्य के हित में है और न ही पार्टी के.

फिर भी पिछले अनुभवों के मद्देनजर कौल के बयान का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि इंका आलाकमान ने चव्हाण को हटाने की मांग नामंजूर कर दी है. क्योंकि राजीव गांधी चव्हाण को समर्थन देने या हटाने के बारे में अभी कोई निश्चित फैसले पर नहीं पहुंच पाए हैं. इंका आलाकमान हर समय परस्पर विरोधी संकेत देता रहता है. मार्च में लगता था कि चूहा-बिल्ली की इस दौड़ का अंत अब आ गया है. पर चव्हाण की किस्मत का पारा बहुत तेजी से नीचे-ऊपर आने के बावजूद वे बच गए.

कुछ समय की शांति के बाद चव्हाण फिर हमले की जद में हैं. कौल के दौरे से कुछ पहले दो पूर्व मुख्यमंत्रियों पाटील और शरद पवार ने साझा मोर्चा बना लिया. उनके समर्थकों (120 विधायकों का दावा है) ने कौल से चव्हाण को हटाने की मांग की और उन्हें संभावित उत्तराधिकारियों की एक सूची भी दी. इसमें पवार, निलंगेकर, सांसद प्रतापराव भोसले और पूर्व उपमुख्यमंत्री रामराव आदिक के नाम थे. बस नहीं था तो पाटील का नाम, हालांकि हर कोई जानता है कि वे चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का रिकार्ड कायम करने के लिए तैयार बैठे हैं. बंबई के सांसद शरद दिघे के मुताबिक, "दादा गहरी चाल चल रहे हैं. वे सभी असंतुष्ट नेताओं की पीठ तो ठोंक रहे हैं पर आखिरी वक्त में जब आलाकमान को

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इनमें कोई भी मान्य नहीं होगा तो वे खुद मैदान में कूद पड़ेंगे."

मगर दो साल में पहली बार चव्हाण के पाले के लोगों में भी सक्रियता दिखी. अनेक मंत्री और विधायक (दावा 180 का है) चव्हाण के करीबी दोस्त और सांसद बालासाहब विखे पाटील के सरकारी बंगले पर जमा हुए. फिर भी किसी पक्ष के पास इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब नहीं था कि अगर आलाकमान का ढुलमुल रवैया बरकरार रहा तो क्या वे खुली लड़ाई के लिए तैयार हैं.

चव्हाण के एक विरोधी ही खुलकर मैदान में आए हैं. मुख्यमंत्री के गृहक्षेत्र के ही बालासाहब पवार ने अपनी धमकी के मुताबिक राजीव गांधी को अपना इस्तीफा भी भेज दिया. औरंगाबाद नगरपालिका चुनावों में शिवसेना के हाथों इंका के पिट जाने के बाद उन्हें लगता है कि चव्हाण प्रदेश में पार्टी को तबाह कर देंगे. पर चव्हाण की शिकायत है, "उनके सभी 10 उम्मीदवार पालिका चुनावों में हारे. फिर अपनी गलती के लिए वे मुझी से इस्तीफा चाहते हैं."

हालांकि चव्हाण को बीएड कॉलेजों से संबंधित एक घोटाले, बाबासाहब आंबेडकर की 'रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म' के प्रकाशन पर उठे राज्यव्यापी बवाल और बंबई के एक विधानसभा उपचुनाव में शिवसेना की जीत सरीखे कई तूफानों से दो-चार होना पड़ा है, फिर भी उन्होंने यह आभास नहीं होने दिया कि राज्य का प्रशासन उनके हाथ से निकल रहा है. दूसरी तरफ उनकी सरकार ने राज्य में आए भीषण सूखे का काफी कुशलता से सामना किया. उन्हें सिंचाई जल के न्यायोचित बंटवारे और सहकारी संस्थाओं के कामकाज में लोकतंत्रीकरण के सवालों पर भी सहकारी चीनी मिलों की ताकतवर लॉबी से जूझना पड़ा. हाल ही में खेतिहर मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी दुगनी करने का महत्वपूर्ण फैसला भी उनकी सरकार ने ही लिया. यह मुद्दा अरसे से लटका चला आ रहा था.

चव्हाण ने न्यूनतम मजदूरी के सवाल पर पिछले साल एक समिति बनाई थी जिसने छह महीने में ही अपनी रिपोर्ट दे दी और उन्होंने इसे तुरंत ही चालू साल के बनाए जा रहे बजट में शामिल कर लिया. मजदूरी 6 रु. से बढ़ाकर 12 रु. कर दी गई जिससे महाराष्ट्र के 65 लाख खेतिहर मजदूरों को फायदा हुआ. पर अगर मानसून ने इस साल भी धोखा दिया तो सरकार को इस बढ़ोतरी का वित्तीय खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा. ऐसी हालत में उसे सूखापीड़ित जिलों में रोजगार गारंटी योजना के तहत पिछले साल के 250 करोड़ रु. के खर्च की राशि को दुगना करना पड़ेगा.

इस सवाल पर चव्हाण के रुख से उनकी मजबूती और कमजोरी दोनों ही जाहिर होती हैं. यानी जब कोई मामला उनकी समझ में आ जाता है तो वे खुले दिमाग से तुरंत फैसला लेते हैं. उनके इसी गुण ने इन्हें नौकरशाही में भी लोकप्रिय बनाया है. पर यह भी लगता है कि वे अक्सर अपनी कार्रवाई के राजनैतिक नतीजों को नजरंअदाज कर देते हैं. इस मामले में भी यही हुआ और अमीर किसानों की लॉबी उनसे और कट गई. एक वरिष्ठ अफसर कहते हैं, "चव्हाण के रुख ने प्रशासन के नजरिये को नया विस्तार दिया है. वे हमेशा दूरगामी नजरियें से सोचते हैं, कामचलाऊ तरीके से नहीं."

प्रशासन के कामकाज में महत्वपूर्ण बदलाव यह आया है कि अब इसमें ज्यादा खुलापन है. चव्हाण सरकार ने इस साल विधानसभा में योजना की लंबी-चौड़ी मध्यावधि समीक्षा पेश की और अब वह सरकारी खर्च पर श्वेतपत्र भी तैयार कर रही है. पर सरकार को विपक्षियों की लगातार आलोचना झेलनी पड़ रही है. कुछ हद तक यह इसलिए भी है कि चव्हाण की अनुभवहीन मंत्रियों की छोटी सी टीम कारगर ढंग से काम नहीं कर पा रही. विपक्ष के नेता और कृषक कामगार दल के दत्ता पाटील कहते हैं, "सुशील कुमार शिंदे (वित्त), बिलासराव देशमुख और रोहिदास पाटील (दोनों राजस्व) के अलावा 18 मंत्रियों में से किसी ने भी कोई छाप नहीं छोड़ी है. चव्हाण तो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार तक नहीं कर सकते. जाहिर है कि जब तक वे दिल्ली से बंधन मुक्त नहीं होते, सरकार नहीं चला सकते."

हाल ही में विधानपरिषद की सदस्यता से मुक्त हुए जनता पार्टी के सदानंद वर्दे का मानना है कि चव्हाण पार्टी और प्रशासन दोनों पर पकड़ बनाने में नाकाम रहे हैं. वे कहते हैं, "फैसले लेते समय वे गड़बड़ा जाते हैं और फाइलें आगे नहीं सरकतीं." इसके लिए वे करीब 3000 सेकेंडरी स्कूलों के बारे में सरकार की अनिर्णायक स्थिति का हवाला देते हैं. इन स्कूलों को हालांकि बिना अनुदान के चलाने की इजाजत है पर इनमें 600 ही चलने लायक माने जाते हैं.

प्रशासनिक सुस्ती की एक बड़ी वजह यह भी है कि मंत्रियों के पास विभागों की भरमार है. मसलन सरकार में सचिव पद से रिटायर होने के बाद मंत्री बनने वाले वी. सुब्रमण्यम के पास आठ विभाग हैं. आम तौर पर इन विभागों के अलग-अलग मंत्री होने चाहिएं. सुब्रमण्यम कहते हैं, "काम का बोझ बेहद ज्यादा है. हमें कम-से-कम एक दर्जन मंत्री और चाहिए."

नौकरशाह भी यही कहते हैं और खुद चव्हाण भी कई बार मानते हैं कि वे अब 70 के दशक जैसे प्रशासक नहीं रहे. अब वे राजनैतिक रूप से आलोकप्रिय फैसलों को स्थगित रखते हैं जबकि पहले ऐसा नहीं था. खुद मुख्यमंत्री कहते हैं, "मैं गरीबी जैसी कुछ

कार्टून: अजीत नैनन

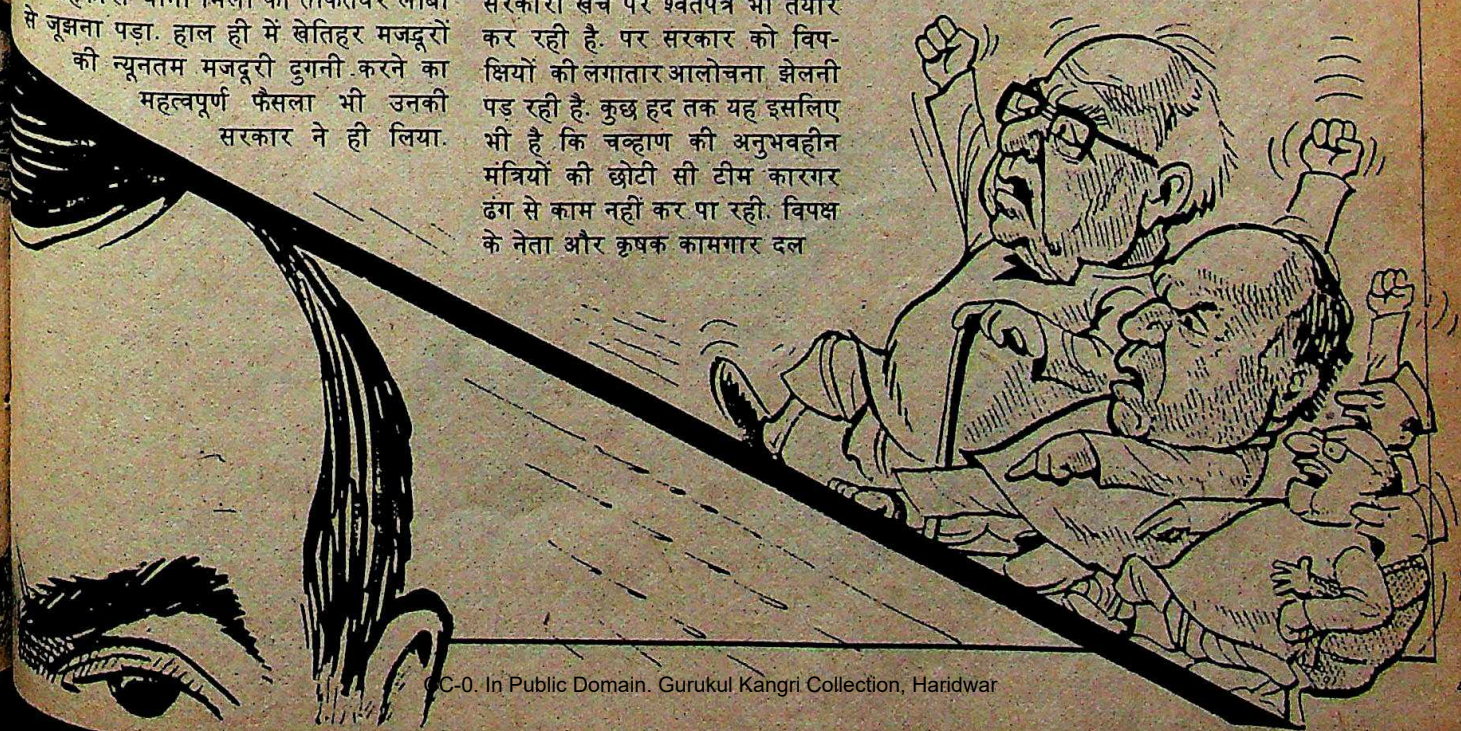

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मूल समस्याओं को निबटाना चाहता हूं, बशर्ते बेकार बातों पर ताकत खर्च न हो."

पर यह कहना आसान है, करना कठिन. जब तक राजीव यह फैसला नहीं करते कि चव्हाण की पीठ पर हाथ धर असंतुष्टों को दबाया जाए या उन्हें हटाकर शरद पवार जैसा कोई युवा और राजनैतिक रूप से उत्साही मुख्यमंत्री बनाया जाए, यह गतिरोध बरकरार रहेगा. जहां चव्हाण और इंका असंतुष्ट पहाड़ी बकरियों की तरह चोटियों पर भिड़ रहे हैं, वहीं नीचे खड़ा शिवसेना का शेर ताकत बटोर रहा है. राज्य विधानसभा के चुनाव में 18 महीने रह गए हैं, इसलिए चव्हाण की किस्मत का फैसला अनिश्चित काल तक के लिए टाला नहीं जा सकता. आलाकमान को जल्द ही न सिर्फ एक नेता की बल्कि महाराष्ट्र में पार्टी की किस्मत का फैसला करना है.

मुलाकात

'चुनौती तो अंदरूनी झगड़ा है'

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण भयंकर दबावों के बीच भी संयम बनाए रखते हैं. उनका दूसरा गुण कार्यकुशलता के प्रति उनकी श्रद्धा है. बंबई मंत्रालय स्थित उनके दफ्तर में करीने से सजी मेज को देखकर उनके दूसरे गुण का कुछ अंदाज लग जाता है. उनकी अपनी स्थिति के बारे में अनिश्चितता का राज्य पर क्या असर पड़ रहा है, इस पर ब्यूरो प्रमुख ***एम. रहमान*** *ने चव्हाण से बातचीत की. उसके अंश:*

● ***शीला कौल के बंबई दौरे के बाद मुख्यमंत्री पद पर आपके बने रहने के बारे में जोरदार अटकलें लगाई जाने लगी हैं.***

जब भी कोई इंका महासचिव यहां दौरे पर आता है तो इसका अर्थ यही लगा लिया जाता है कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन होने वाला है. लेकिन इसमें रत्ती भर सचाई नहीं. हाल में जब शीला कौल बंबई आईं तो वे राज्य के हालात जानने के लिए बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलना चाहती थीं. पर इसके बदले राज्य इंका कमेटी ने उनसे मिलने के लिए सांसदों, विधायकों और जिला परिषद के अध्यक्षों को बुला लिया. कुछ लोग केंद्रीय पदाधिकारियों के हर दौरे को नेतृत्व परिवर्तन के मुद्दे के रूप में तब्दील कर देना चाहते हैं.

● ***शीला कौल ने यह बयान दिया कि बार-बार नेतृत्व परिवर्तन राज्य या पार्टी के हित में नहीं है. क्या आप इस बयान को आप में विश्वास जाहिर करने की सार्वजनिक घोषणा मानते हैं?***

मैं यह नहीं कहूंगा. उनके लिए अभी से मन बना लेना जल्दबाजी होगी.

● ***इस अनिश्चय की स्थिति से आपके कामकाज पर असर नहीं पड़ेगा?***

जब खुले आम ऐसी चर्चा होने लगती है तो उसका असर अफसरशाही, पार्टी कार्यकर्ताओं के मनोबल और फैसला लेने की सरकार की क्षमता पर पड़ता ही है.

● ***आपके मंत्रिमंडल का आकार छोटा होना भी क्या एक समस्या नहीं?***

हां, लेकिन सभी मंत्री ठीक-ठाक काम कर रहे हैं. फिर भी कोई व्यक्ति, चाहे वह कितना ही काबिल क्यों न हो, उसके काम करने की सीमाएं हैं. लेकिन ऐसा नहीं कि हम उलझ गए हैं और कोई फैसला नहीं ले पा रहे.

● ***क्या औरंगाबाद नगरपालिका चुनावों के बाद राज्य में इंका के लिए अब शिवसेना बड़ी चुनौती नहीं बन गई है?***

भवान सिंह

बड़ी चुनौती तो इंका का अंदरूनी झगड़ा है. अगर वह बंद हो जाए तो शिवसेना की हवा खुद-ब-खुद सरक जाएगी. उसके साथ कोई जनसमर्थन तो है नहीं. वह सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने की कोशिश करती है.

● ***इंका में अंदरूनी झगड़े कैसे रुकेंगे?***

पहली चीज तो अनुशासन कायम करना है. लोगों को जिम्मेदारी का एहसास कराया जाए. ऐसा हो जाए तो मुझे यकीन है कि इस समय दिख रहा सारा असंतोष खत्म हो जाएगा.

● ***अनुशासन कायम कौन करेगा?***

(हंसते हुए) आप मुझसे कहलवाना चाहते हैं कि आलाकमान यह काम करे. बिलाशक आलाकमान को ही अनुशासन लागू करना होगा.

● ***आरोप यह भी है कि आप अपने परिवार के लोगों की मदद कर रहे हैं.***

मेरा बेटा मूल रूप से व्यवसायी है. सांसद बनने से पहले उसके पास (नांदेड़ में) कई एजेंसियां थीं. उसे कोई एजेंसी दिलाने में मेरा कतई हाथ नहीं रहा. न ही लोकसभा का टिकट मैंने उसे दिलाया. प्रधानमंत्री ने मुझसे पूछा कि मेरे बेटे को अगर पार्टी टिकट दिया जाए तो क्या वह जीत सकता है. मैंने हां में जवाब दिया.

ठीक यही मेरे दामाद के साथ भी है. मेरी बेटी के साथ शादी होने के पहले से ही वह इंका में है.

फिर आम आरोप यह भी है कि मंत्रिमंडल में आधे दर्जन से अधिक लोग मेरे रिश्तेदार हैं. मैं चुनौती देता हूं कि वे बताएं कि ऐसे मंत्री कौन हैं. हो सकता है कि कोई मेरा दूर का रिश्तेदार हो. वैसे तो यशवंतराव चव्हाण भी मेरे रिश्तेदार थे. दादा के सांसद बेटे के बारे में कोई यही सवाल क्यों नहीं करता? क्यों नहीं वे विधानसभा में शरद पवार के रिश्तेदारों पर उंगली उठाते? विधानसभा के उपाध्यक्ष उनके बहुत करीबी रिश्तेदार हैं.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

श्वेतपत्र का संकट

सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के कामकाज पर श्वेतपत्र बनाने का इरादा ठंडा पड़ गया लगता है. 1987 के अपने बजट भाषण में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि सरकार संसद में एक श्वेतपत्र पेश करेगी जिसमें सरकार और उसके व्यावसायिक उद्यमों के करीबी रिश्ते के बारे में पर्याप्त बातें होंगी. इस श्वेतपत्र के कम से कम तीन मसौदे बने भी. पिछली जुलाई में अंतिम मसौदा बना जिसमें मूल प्रारूप की व्यवस्थाओं को एकदम हल्का बना दिया गया था. सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के प्रमुखों की बैठक में इस पर बहुत गरमागरम बहस हुई. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस मामले को 12 मंत्रियों के समूह को सौंप दिया जिसकी बैठक करीब एक पखवाड़े पहले हुई थी लेकिन अधिकांश मंत्रियों ने मसौदे को पढ़ा नहीं था, इसलिए बैठक चल नहीं पाई. अब उम्मीद की जा रही है कि ये मंत्री अपने सहायकों के साथ कोई बैठक करेंगे. लेकिन इसमें अभी और समय लगने की संभावना है.

बहुमंजिले इरादे

जायदाद की खरीद-फरोख्त के मामले में निजी क्षेत्र की कंपनियों की होड़ कुछ अधिक ही तेज हो गई है. शॉ वैलेस कलकत्ता में बहुमंजिली रिहाइशी इमारतें बनाने के लिए एक सहायक कंपनी बना चुकी है. भरपूर नकदी वाली ग्रेट ईस्टर्न कंपनी सस्ते दाम पर फ्लैट और दफ्तर बनाने के लिए बंबई और उसके आसपास जमीन खोज रही हैं. एसीसी भी सीमेंट के अपने कारोबार के बाद गृहनिर्माण को अपने विस्तार का स्वाभाविक क्षेत्र मान रही है. मकानों की कमी के मद्देनजर कंपनियों का यह रुझान समझ में भी आता है. सरकार का अनुमान है कि 1981 से 2001 के बीच 6.38 करोड़ मकानों की जरूरत होगी जिसमें से 1.1 करोड़ मकान तो महानगरों में ही बनाने होंगे. इस काम पर 1800 अरब रुपए खर्च होंगे (1984-85 की दरों पर). इसमें से अभी तक मात्र 35,000 करोड़ रुपए लगाए गए हैं.

अब पैकेजिंग का धंधा

शीतल पेय का पाउडर वगैरह बनाने के बाद मद्रास के कोठारी बंधु अब पैकेजिंग के कारोबार में उतरने की सोच रहे हैं. इस समूह की एक सहायक लीजिंग कंपनी जल्दी ही तीन करोड़ रुपए की लागत से कई तह वाले प्लास्टिक के बोतल और कंटेनर बनाने का काम शुरू करेगी. अभी वह संभावित ग्राहकों और बाजार का सर्वेक्षण कर रही है. एक तह वाले बोतल तो अपने देश में बन रहे हैं, पर कोठारी समूह का मानना है कि टमाटर केच-अप या बियर जैसी चीजों के लिए ये उपयुक्त नहीं हैं. तकनीकी सहयोग के लिए जर्मनी और जापान की कंपनियों से बात चल रही है.

जापानी नक्शे कदम पर

इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग कुछ (बौने) अधिकारियों को निकालकर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. और इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के कुछ लोगों को ले आना चाहता है. इस सिलसिले में सार्वजनिक क्षेत्र के कई अधिकारियों का आजकल इंटरव्यू चल रहा है. यह कार्यक्रम सरकार और इस उद्योग के बीच लेन-देन को भी बढ़ाएगा. साथ ही विभाग के अधिकांश नौकरशाह वर्षों से एक ही जगह जमे हुए हैं. विदेशों में इस तरह की अदला-बदली खूब होती है. जापान में यह रिवाज अनेक वर्षों से है. शायद इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग भी जापान के नक्शे कदम पर ही चल रहा है.

गिरावट की रफ्तार घटी

लगता है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के निर्यात में गिरावट रुक गई है. एक आर्थिक अखबार के अनुसार 1986-87 में इनका कुल निर्यात 3,942 करोड़ रु. मूल्य का था जो पिछले साल के 3,822 करोड़ रु. से 3.1 फीसदी अधिक है. यह वृद्धि तो कम है लेकिन भारी गिरावट को देखते हुए यह अच्छा

चार्ट: बी.के. शर्मा

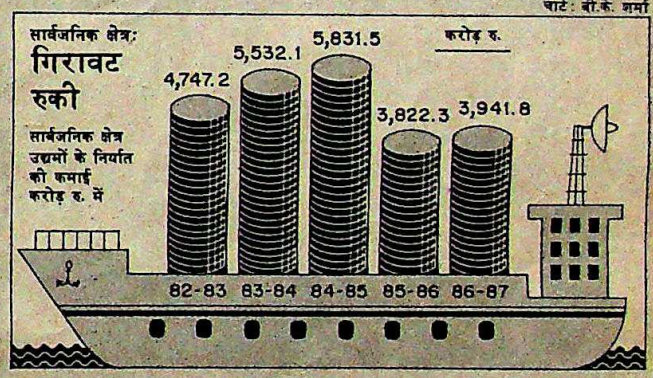

ही है (देखें चार्ट). 1984-85 में 5,831 करोड़ रु. के निर्यात के बाद यह गिर ही रहा था. देश के सकल निर्यात में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की हिस्सेदारी 31 फीसदी होने के कारण भी यह महत्वपूर्ण है.वैसे पिछले और इस साल के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं, इसलिए गिरावट रुकी है या नहीं, यह पता नहीं चलता.

नंबर एक बनेंगे

दुपहिया वाहन बाजार में जबरदस्त होड़ के बावजूद राहुल बजाज ने अपनी कंपनी की वार्षिक उत्पादन क्षमता पांच लाख वाहन से बढ़ाकर 14 लाख करने की अनुमति मांगी है. उम्मीद है कि सरकार जल्दी ही इसकी मंजूरी देगी. सरकार ने बजाज से यह कबूल करवा लिया है कि वह निर्यात से उतनी विदेशी मुद्रा कमा लेंगे जितनी उन्हें अपनी कंपनी की जरूरतों के लिए खर्च करनी होती है. अनुमति मिल गई तो बजाज को अगले पांच वर्षों में 14 करोड़ रु. के स्कूटरों का निर्यात करना होगा. निर्यात करीब 12 फीसदी हो जाएगा. औरंगाबाद के कारखाने की उत्पादन क्षमता तीन लाख वाहन से बढ़ाकर दस लाख करने की योजना है. इसके पुराने लाइसेंस के तहत 25 फीसदी निर्यात की शर्त थी. बजाज दुनिया की तीसरी बड़ी दुपहिया वाहन कंपनी है. अनुमति मिलने के बाद यह नंबर एक बन जाएगी.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मजदूर संघ

विधेयक पर बवाल

सरकार द्वारा कानूनों में भारी रद्दोबदल का प्रस्ताव

देश भर के मजदूर संघों के भीतर एक अजीब अफरातफरी मची हुई है. मजदूरों के संगठित वर्ग के सामने पिछले दस वर्षों में ऐसी बड़ी चुनौती नहीं आई थी. यह चुनौती पेश की है एक विधेयक ने जिसके तहत श्रम कानूनों में भारी रद्दोबदल का प्रस्ताव है. इसके कारण मजदूर संघों के कामकाज पर उलटा असर पड़ेगा. शायद उनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाए.

इस विधेयक के कुछ प्रावधानों से उत्तेजित होकर मजदूर नेता अब इसके खिलाफ राष्ट्र-व्यापी जंग छेड़ने की रणनीति बनाने में जुटे हैं. हड़ताल और प्रदर्शन तो किए ही जाएंगे, रेल कर्मचारियों से काम बंद करने का आह्वान करने की भी चर्चा है. ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक) के अध्यक्ष, सांसद इंद्रजीत गुप्ता कहते हैं, "इस विधेयक के खिलाफ तूफान खड़ा हो जाएगा."

'मजदूर संघ और औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक' नामक इस विवादास्पद विधेयक का मकसद छोटे मजदूर संघों की बाढ़ पर रोक लगाना, मजदूरों में से ही नेतृत्व को बढ़ावा देना और अचानक हड़ताल या तालाबंदी की घोषणा पर पाबंदी लगाना, है (देखें बॉक्स).

विधेयक की प्रमुख बातों में यह भी है कि यह मजदूरों को वरीयता, वेतन और पदोन्नति जैसे सवालों पर प्रबंधकों से विवाद के मामले श्रम अदालत में उठाने के अधिकार देता है. अभी वे सीधे श्रम अदालतों में नहीं जा सकते. सरकार ही विवादों को श्रम अदालतों में भेजती है. इसलिए इस विधेयक के पीछे व्यक्तिगत शिकायतों के जल्दी निबटारे की व्यवस्था है. लेकिन यह विधेयक प्रबंधकों को अदालती झमेलों में तो फंसाएगा ही, मध्यस्थता की मजदूर संघों की भूमिका को भी कमजोर करेगा.

जाहिर है कि मजदूर संघ इस विधेयक को उन पर नियंत्रण लगाने के एक निरंकुश प्रयास के रूप में देखते हैं. मजदूर नेता, सांसद दत्ता सामंत ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्ति की, "अंग्रेजों ने 1947 में औद्योगिक विवाद कानून बनाया लेकिन उन्होंने हड़ताल पर पांबदी लगाने की नहीं सोची थी. परंतु आजाद भारत में राजीव गांधी हड़ताल पर पांबदी लगाने की सोच रहे हैं."

और दूसरी ओर से व्यक्त की जा रही प्रतिक्रियाएं इसके समर्थन में हैं. फिक्की के अध्यक्ष रोहित मेहता कहते हैं, "सद्भावपूर्ण औद्योगिक संबंधों के लिए जरूरी स्वस्थ मजदूर आंदोलन की दिशा में पहल के लिए सरकार को बधाई देनी चाहिए." मगर मेहता इस विधेयक की कई बातों से असहमत भी हैं मसलन गैरकानूनी तालाबंदी के लिए मालिकों की ज्यादा सजा का प्रावधान या सरकार को दखलंदाजी के ज्यादा अधिकार देने की व्यवस्था आदि. भारतीय नियोक्ता संघ के अध्यक्ष केशव महिंद्रा कहते हैं, "यदि सरकार ने इस विधेयक को बनाने के पहले प्रबंधकों और मजदूर संघों दोनों से बात की होती तो कई खामियां दूर हो सकती थीं."

इस्पात प्राधिकरण के कार्मिक निदेशक एम.आर.आर. नैयर कहते हैं, "इससे मौजूदा अराजकता कुछ हद तक दूर होगी." यह संभव भी है. आज मजदूर संघों में आपस में ही जबरदस्त होड़ है. फिर, आज कानून में मजदूर संघों की मान्यता का प्रावधान नहीं है. राज्य सरकारें ही इस बारे में अपनी समझ और जरूरत से फैसला करती हैं.

वैसे इन समस्याओं का एहसास काफी पहले से है. इसलिए 1978 में जनता सरकार ने भी लगभग ठीक यही विधेयक लाना चाहा था पर मजदूर संघों के तेवर देखकर वह पस्त हो गई थी. बाद में कई सरकारी समितियों ने भी सरकार से इस स्थिति में सुधार लाने की मांग की.

फिर भी विधेयक की कई धाराएं मजदूर संघों और प्रबंधकों दोनों पर ही कई अमिट दाग छोड़ जाएंगी. नई शर्तों को ही लीजिए. जैसे मजदूर संघों के पंजीकरण का ही मामला लें. इसके लिए कुल मजदूरों में से 10 फीसदी का समर्थन जरूरी होगा. इससे डीसीएम और इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) जैसे निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में अनेक छोटे-छोटे मजदूर संघों पर कुठाराघात होगा. सेल के बोकारो इस्पात कारखाने में 65 पंजीकृत मजदूर संघ हैं. कुछ की सदस्य संख्या तो मात्र 1,000 के करीब ही है. इस कारखाने में करीब 50,000 कर्मचारी हैं. इसलिए विधेयक के तहत ये छोटे-छोटे संघ पंजीकृत ही नहीं हो पाएंगे और उन्हें मान्यता भी नहीं मिल पाएगी.

विधेयक का यही मकसद भी है. लेकिन इसके बावजूद इसके प्रावधान काफी कड़े और गैर-यथार्थपरक हैं. जैसा कि टीवीएस समूह के उद्योगपति सुरेश कृष्ण कहते हैं कि यह शर्त छोटी कंपनियों के लिए तो सही है, पर जिन कंपनियों में मजदूरों की संख्या काफी ज्यादा है वहां तो कई मज़दूर संघ पंजीकरण के लिए जरूरी 10 फीसदी समर्थन नहीं ही जुटा पाएंगे. भाकपा के सांसद गुरुदास दासगुप्त कहते हैं कि पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड के राज्य भर में 44,000 कर्मचारी हैं. किसी मजदूर संघ को पंजीकरण के लिए 4400 कर्मचारियों के दस्तखत प्राप्त करना असंभव जैसा ही होगा.

इसके साथ ही विधेयक की कुछ दूसरी धाराएं भी उतनी ही गैर-यथार्थपरक हैं. किसी संघ के पदाधिकारियों में 'बाहरी तत्वों'

"विधेयक में गैर-कानूनी तालाबंदी से संबंधित प्रावधानों से मैं सहमत नहीं हूं."

रोहित मेहता,
अध्यक्ष, फिक्की

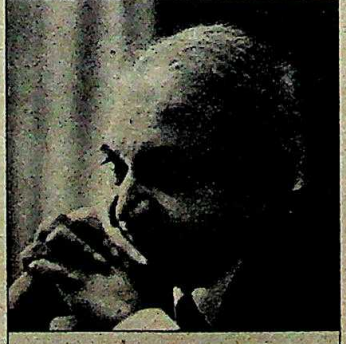

"सरकार को प्रबंधकों और मजदूर संघों के प्रतिनिधियों से बातचीत करनी चाहिए थी."

केशव महिंद्रा,
अध्यक्ष, भारतीय नियोक्ता संघ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"मज़दूर संघ और औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक के खिलाफ तूफान खड़ा हो जाएगा."

इंद्रजीत गुप्ता,
सांसद और अध्यक्ष, एटक

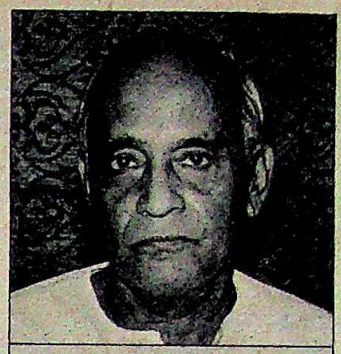

"विधेयक का मकसद अच्छा है. इसके बारे में उठाई जाने वाली ज्यादातर आपत्तियां राजनैतिक हैं."

जी. रामानुजम,
अध्यक्ष, इंटक

"अंग्रेजों ने भी हड़ताल पर पाबंदी नहीं लगाई. परंतु राजीव गांधी पाबंदी लगाने की सोच रहे हैं."

दत्ता सामंत,
मजदूर नेता और सांसद

की संख्या मात्र दो तक सीमित रखने का प्रस्ताव है. और यह विधेयक मजदूर संघ की कार्यकारी समिति में किसी मंत्री के होने पर पाबंदी लगाता है. सिद्धांत रूप में तो इससे अनेक मजदूर नेताओं को अपना पद छोड़ना पड़ेगा. मसलन ताकतवर संघ अखिल भारतीय गोदी कर्मचारी संघ (ऑल इंडिया पोर्ट ऐंड डॉक वर्कर्स फेडरेशन) के तीन सचिव और उतने ही सहायक सचिव तथा एक कोषाध्यक्ष बाहरी व्यक्ति हैं. इसी तरह पश्चिम बंगाल के परिवहनमंत्री श्यामल चक्रवर्ती (जो कि बड़े संघों के प्रमुख हैं), श्रममंत्री शांति घटक और मुख्यमंत्री ज्योति बसु समेत कई मंत्रियों को सीटू से अपना संबंध तोड़ना होगा.

तीसरे, विधेयक में धीरे काम करने की जो परिभाषा दी गई है उसके अनुसार ऐसा कोई कदम जिससे काम पर खास प्रभाव पड़े, धीरे काम करना माना जाएगा. पर अदालत इसकी अलग व्याख्या कर सकता है. इस के अलावा विधेयक में यह भी है कि धीमे काम की अवधि के दौरान मजदूरों को कितना वेतन मिलेगा इसका फैसला अदालत करेगी. इस प्रावधान से प्रबंधकों की कंपकंपी छूट गई है तो उधर मजदूरों के वेतन से मजदूर संघों का मासिक चंदा काटने का अधिकार प्रबंधकों को दिए जाने से मजदूर संघों में भी घबराहट फैली हुई है. कपड़ा उद्योग में प्रचलित यह व्यवस्था संघों की ताकत जांचने में सहायक सिद्ध होगी और इससे गुप्त मतदान की व्यवस्था खत्म हो जाएगी. मजदूर नेताओं को डर है कि प्रबंधक अपने मनपसंद संघों में शामिल होने के लिए मजदूरों को मजबूर करेंगे.

लेकिन इस सबके बावजूद इस 'जांच व्यवस्था' का पक्ष लेने वाला इंकाई मजदूर संघ इंटक है. दरअसल इंटक गुप्त मतदान का विरोधी रहा है. इसलिए इसके विरोधियों के मुताबिक इंटक को डर है कि यदि मजदूरों का गुप्त मतदान होता है तो वह अपना नियंत्रण खो बैठेगी. हालांकि इंटक के अध्यक्ष जी. रामानुजम जवाब देते हैं, "जांच व्यवस्था अधिक स्थायी व्यवस्था है. गुप्त मतदान से कई भ्रष्ट तरीके भी पनपेंगे (जैसे वोट बटोरने के लिए शराब बांटना आदि)."

आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच सभी पक्षों की अलग-अलग दलील है. इस तरह मजदूर बंटे हुए हैं. दरअसल, इंटक विधेयक का समर्थन करता है. रामानुजम घोषणा करते हैं, "विधेयक की भर्त्सना के पीछे कोई तर्क नहीं है. विधेयक के बारे में उठाई जाने वाली ज्यादातर आपत्तियां राजनैतिक हैं. इसका मकसद भला करना ही है." यानी सरकार मजदूर संघों के हंगामे पर कान नहीं देगी. 1988 में सरकार और भी अधिक विवादास्पद प्रावधान गले उतारने की कोशिश करेगी. लेकिन अभी शायद वह अगले आम चुनाव पर नजर रखे हुए है.

—पलकनाथु जी. मथाई, बंबई में
सलिल त्रिपाठी, मद्रास में एस.एच. वेंकटरमनी और कलकत्ता में कमलजीत रतन की रिपोर्टों के साथ

औद्योगिक कानून संशोधन विधेयक के प्रमुख अंश

- गैर-कानूनी हड़तालों और तालाबंदियों पर कैद के अलावा संघों का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है. समझौता समिति में यूनियनों के तीन-चौथाई प्रतिनिधियों का समर्थन अनिवार्य होगा.
- धीमी गति से काम करने के आंदोलन के तहत वे सभी गतिविधियां आएंगी जिनसे काम बंद हो जाए या उसमें रुकावट पड़े.
- 100 से अधिक कर्मचारियों वाले किसी भी प्रतिष्ठान के कम-से-कम 10 फीसदी कर्मचारियों को किसी संघ के पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा.
- जांच की ऐसी व्यवस्था किए जाने का भी प्रावधान है जिसके तहत मजदूर एक सरकारी अधिकारी की उपस्थिति में मालिकों को अपने वेतन में से संघ के लिए मासिक चंदा काट लेने का अधिकार देंगे. इससे मजदूरों के गुप्त मतदान की जरूरत नहीं रहेगी.
- अब दो बाहरी व्यक्ति ही संघ के पदाधिकारी बन सकेंगे. कोई मंत्री या औद्योगिक कानून के तहत सजा भुगत चुका कोई व्यक्ति संघ का पदाधिकारी नहीं हो सकता.
- अगर कोई मालिक किसी मजदूर की छंटनी करता है या उसे नौकरी से निकाल देता है अथवा उसकी सेवा शर्तों में तब्दीली करता है तो इस मामले में किसी दूसरे मजदूर के शामिल न रहने की सूरत में भी कोई विवाद उठने पर उसे औद्योगिक विवाद माना जाएगा. सेवा शर्तों में वेतन, पेंशन, नौकरी पक्का होना, वरिष्ठता, पदोन्नति, छुट्टी की सुविधाएं और मजदूर के खिलाफ किसी भी किस्म की अनुशासनात्मक कार्रवाई शामिल है. अगर यह विवाद 60 दिन के अंदर नहीं निबटाया जाता तो मजदूर पंचाट के लिए किसी श्रम न्यायालय में जा सकता है.
- श्रम न्यायालय के फैसलों पर अपील की सुनवाई के लिए केंद्र तथा राज्य स्तर पर औद्योगिक संबंध आयोग गठित किए जाएंगे. इन आयोगों के फैसलों को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में ही दी जा सकेगी.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

औद्योगिक नीति

उदारवाद का दूसरा दौर

एक ही झटके में जटिल नियंत्रण व्यवस्था को ढीला किया गया

पिछले साल हुए एक के बाद एक धमाकों से काफी सारे शोर दब गए थे. इनमें औद्योगिक उदार नीति का शोर भी शामिल था. पर अब वह फिर धूमधाम के साथ अपने पहले वाले रंग में वापस आ गया है.

पिछले पखवाड़े औद्योगिक हलके में बहुत खुशी थी. इसका कारण भी था. औद्योगिक नीति में अचानक ही बड़े बदलाव ला दिए गए थे. एक ही झटके में सरकार ने उद्योगों पर लगाई अपनी जटिल नियंत्रण व्यवस्था को और ढीला कर दिया. हां, एकाधिकार कानून और विदेशी मुद्रा विनिमय कानूनों के तहत आने वाली बड़ी कंपनियों को जरूर इस व्यवस्था से बाहर रखा गया है. नई नीति की मुख्य बातें हैं.

- निवेश की सीमा पर ध्यान न देते हुए अब 27 खास उद्योगों में ही लाइसेंसों की जरूरत होगी (सार्वजनिक और लघु क्षेत्रों के लिए आरक्षित उद्योग इस सीमा से बाहर ही रहेंगे).
- केंद्र द्वारा घोषित पिछड़े इलाके में 50 करोड़ रु. से कम लागत पर लगने वाले किसी भी उद्योग के लिए अब लाइसेंस लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी.
- 21 महानगरों से खास-खास दूरी के बाहर लगने वाली 15 करोड़ रु. तक की इकाइयों के लिए भी लाइसेंस लेना जरूरी नहीं होगा. पहले यह लाइसेंस न लेने की सीमा पांच करोड़ रु. थी.
- 30 फीसदी से कम आयातित कच्चा माल और उपकरणों से चलने वाली योजनाओं के लिए भी लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी. पहले यह सीमा 15 फीसदी थी.

यह घोषणा राजीव गांधी के सत्ता में आने के बाद उदारवाद के दूसरे दौर की शुरुआत कही जा सकती है. उद्योग राज्यमंत्री एम. अरुणाचलम कहते हैं, "हमारा मकसद एक ही झटके में उदारवाद लाना कभी नहीं रहा. यह तो एक प्रक्रिया है. छोटी-छोटी बाधाएं जरूर हटनी चाहिए और हटेंगी भी." उद्योग मंत्रालय के अधिकारी एक कदम और आगे बढ़कर दावा करते हैं कि उदारवाद का यह लक्ष्य पूरा कर लिया गया है.

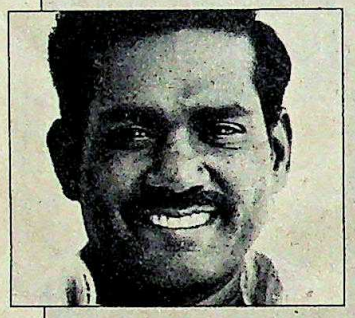

"हमारा एक ही झटके में उदारवाद लाने का मकसद कभी नहीं रहा... छोटी-छोटी बाधाएं हटनी चाहिए"

एम. अरुणाचलम
उद्योग राज्यमंत्री

"इससे यही साबित होता है कि औद्योगिक उदारता की नीति एक बहाव की तरह है जो कहीं नहीं रुकता"

रौनक सिंह
अध्यक्ष, रौनक समूह

दरअसल पुरानी प्रक्रिया को देखने से लगता भी है कि इन लोगों की बात सही हो सकती है. औसतन पिछले पांच वर्षों में सरकार द्वारा करीब 83 फीसदी औद्योगिक अधिकारपत्र एकाधिकार और विदेशी मुद्रा कानूनों के दायरे में न आने वाली कंपनियों को ही मिले. इसलिए नई उदार नीति का असर उद्योग के इस क्षेत्र में तो व्यापक रूप से होगा.

इसके अलावा इनमें से अधिकांश प्रस्ताव वित्तीय लिहाज से इतने बड़े नहीं थे कि उनसे किसी बड़े नतीजे की उम्मीद की जाती. करीब 85 फीसदी मामलों में 10-10 करोड़ रु. से भी कम का निवेश होना था. अब नए नियमों के आ जाने से इनमें से अनेक छोटे उद्यमियों को सुविधा होगी और उन्हें सारी कागजी कार्रवाई पूरी करने की जगह सिर्फ अपना पंजीकरण कराना होगा.

मंत्रालय के एक बड़े अधिकारी बताते भी हैं, "हम इस बात का इंतजाम कर रहे हैं कि आइंदा हमारे पास अभी तक आने वाले प्रस्तावों के एक-तिहाई प्रस्ताव ही आएं. इससे बाकी काम भी तेजी से निबटेंगे." लेकिन यह बात भी सही है कि इन एक-तिहाई प्रस्तावों में ही करीब 70 फीसदी निवेश की बात होती है. काम का बोझ बहुत हल्का हो जाने से खुश अधिकारियों का कहना है कि अब वे अपने पास आए आवेदनों के बारे में जल्दी फैसले ले सकते हैं. लेकिन सच यह है कि निजी क्षेत्र का अधिकांश निवेश नियंत्रित ही है.

उदार नीति बनाने के क्रम में पहले भी कुछ उद्योग एकाधिकार और विदेशी मुद्रा कानूनों की सीमा में आने वाली कंपनियों के लिए भी लाइसेंसमुक्त किए जाते रहे हैं. मार्च 1985 में 25 उद्योगों को लाइसेंसमुक्त किया गया. बाद में पिछड़े इलाकों में नए निवेश की शर्त पर एकाधिकार और विदेशी मुद्रा कानूनों की सीमा में आने वाली कंपनियों के लिए भी लाइसेंस की अनिवार्यता खत्म कर दी गई. फिर, अपने उत्पादों की सूची को बढ़ाने के मामले में 34 और उद्योगों के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं रह गई. और क्षमता बढ़ाने के मामले में भी कागजी झमेले को कम कर दिया गया. उसके अलावा आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए 72 चुनिंदा उद्योगों के लिए न्यूनतम उत्पादन स्तर तय कर दिया गया. उद्योग बाजार की स्थिति से ही नियंत्रित हों और उन पर प्रत्यक्ष सरकारी नियंत्रण कम हो, यह कोशिश स्पष्ट रूप से हो रही है. औद्योगिक विकास में इन उपायों का क्या असर होगा इस बारे में भविष्यवाणी करना अभी जल्दबाजी होगी.

दरअसल अब घोषित नीति के अनुसार विदेशी मुद्रा और एकाधिकार कानूनों की सीमा में नहीं आने वाली कंपनियां बिना लाइसेंस लिए कोई इकाई लगा सकती हैं बशर्ते कि उसमें 15 करोड़ रु. से कम निवेश हो, वह पिछड़े इलाके में हो, उन 27 उद्योगों में न हो जिनके लिए लाइसेंस अनिवार्य है तथा उसे पहले दिन से ही 30 फीसदी से

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ज्यादा आयातित कच्चे माल की जरूरत न हो. इन शर्तों के बावजूद भारतीय उद्योगों के लिए उदार नीति लाने का काम अब पूरा होता दिख रहा है.

करीब छह महीने के विचार-विमर्श के बाद जो घोषणा हुई उस पर शुरू में बहुत कम लोगों को भरोसा हुआ. अधिकारी वर्ग के लिए भी यह अचंभा था क्योंकि मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलात संबंधी कमेटी की 2 जून की बैठक में जो नोट रखा गया उसमें भी लाइसेंसमुक्त रखने की सीमा 25 करोड़ रु. ही मुकर्रर की गई थी. लेकिन घोषणा के बाद राजीव सरकार द्वारा शुरू की गई उदार औद्योगिक नीति में लोगों का भरोसा पक्का ही हुआ.

और दरअसल इन्हें लाने के लिए यही समय उपयुक्त था भी. आम तौर पर यह माना जाने लगा था कि उदार औद्योगिक नीति की बात ठंडे बस्ते में डाल दी गई है और अभी तक की गई पहल पर पानी फिर गया है. मसलन 1987 के शुरू में नई औद्योगिक नीति के बारे में एक दस्तावेज पर विचार शुरू हुआ था, पर बाद में उसे एकदम भुला दिया गया. पिछले पखवाड़े की गई घोषणा में प्रमुख भूमिका निभाने वाले योजना आयोग के सदस्य,आबिद हुसैन बताते हैं, "जो कुछ किया जाना था उससे पीछे हटने की तो बात ही नहीं थी. बहस का मुद्दा यह था कि इसकी रफ्तार कैसे बढ़ाई जाए और किस हद तक बदलाव अभी जरूरी हैं."

योजना आयोग के वरिष्ठ सदस्यों के अनुसार उदारवाद की इस मुहिम के कुछ मुद्दों पर पुनर्विचार जरूरी भी था. क्योंकि शुरू की उदार नीतियों पर प्रतिक्रिया मिली-जुली रही थी और इससे औद्योगिकरण की प्रक्रिया पर बुरा असर पड़ा था.

इसलिए उदारवाद का दूसरा दौर शुरू करने से पहले काफी कुछ सोच-विचार कर लेने का फैसला किया गया. पिछले साल बजट में भी कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दिए जाने के साथ उदार नीति को ठंडे बस्ते में जाने के संकेत मिलते थे.

क्या लाइसेंसमुक्ति के लिए औद्योगिक इकाइयों को पिछड़े इलाकों में लगाने की पूर्व शर्त रखना इतनी महत्वपूर्ण बात है? उद्योग जगत के लोगों को ऐसा ही लगता है. इन बदलावों से खुश फिक्की के उपाध्यक्ष और रौनक उद्योग समूह के अध्यक्ष रौनक सिंह कहते हैं, "इससे यही साबित होता है कि औद्योगिक उदारता की नीति एक बहाव की तरह है जो कहीं नहीं रुकता." मोदी जेरॉक्स के अध्यक्ष डॉ. बी.के. मोदी कहते हैं, "लाइसेंस नीति में पहले किए गए परिवर्तनों के साथ नए को जोड़कर देखने से यह बहुत बड़ी चीज लगती है." पंजाब हरियाणा दिल्ली चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष और बाटा इंडिया के प्रमुख एम.एम. सभरवाल मानते हैं, "सरकार अगर अपनी योजनानुसार जरूरी संरचनात्मक चीजें जुटा दे तो व्यापारी वर्ग उत्साहित होगा ही."

लेकिन उन्हें लागू कराना अधिक महत्वपूर्ण है. औद्योगिक विकास में क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के लिए पहले जो कोशिशें हुई हैं, उनमें सफलता नहीं मिली. पिछड़े इलाकों में जाने में कई मुश्किलें भी जुड़ी होती हैं. इंजीनियरिंग उद्योग संगठन के पूर्व अध्यक्ष मनमोहन सिंह इस बारे में बहुत स्पष्ट हैं. वे कहते हैं, "सिद्धांत रूप से लाइसेंस हटाना तो बढ़िया है लेकिन सिर्फ भाषण देने से काम नहीं चलता. महानगरों से हटकर उद्योग स्थापित करने में ढेर सारी मुश्किलें भी जुड़ी हुई हैं."

इसके जवाब में नई घोषणा में सरकार ने पिछले साल बैजल कमेटी द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर विकास केंद्र बनाने का फैसला किया है. चुनिंदा जगहों पर निवेश (300 पिछड़े जिलों में बनने वाले 100 केंद्रों पर 25-25 करोड़ रु.) केंद्रित करके सरकार इस बात का प्रबंध कर रही है कि संरचनात्मक सुविधाओं के अभाव से फिर पहले की तरह बाधा नहीं आए. उद्योग मंत्रालय के अधिकारियों का हालांकि यह भरोसा है कि अगले पांच वर्षों में इसका असर होगा पर स्रोतों का अभाव फिर भी आड़े आ सकता है.

हो सकता है कि इसके बाद भी सारी मुश्किलें दूर न हों लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यही सबसे बढ़िया संभव तरीका है. पूर्व उद्योग सचिव संतोष सोंधी कहते हैं, "पिछड़े इलाकों में लगने वाली इकाइयों को अनेक तरह के वित्तीय फायदे दिए जाते हैं. 30 फीसदी देसीकरण के आधार पर लाइसेंसमुक्ति के प्रावधान से विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी." वे आगे कहते हैं कि अब राजनैतिक हस्तक्षेप भी कम होगा. और यह कोई साधारण फायदा नहीं है.

इन नई घोषणाओं से स्वाभाविक रूप से बड़े घरानों को शिकायत रह ही गई है. सभरवाल कहते हैं, "वक्त आ गया है कि एकाधिकार और विदेशी मुद्रा कानूनों की सीमा में आने वाली कंपनियों को वित्तीय उपायों से नियंत्रित किया जाए." उनका मानना है कि लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षण की मौजूदा नीति पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए. यह नीति कई मामलों में नुकसानदेह रही है.

और यहीं इस खेल के पीछे एक सोची-समझी रणनीति नजर आती है. और यह रणनीति है उद्यमियों का एक नया वर्ग पैदा करना. आबिद हुसैन कहते हैं, "छोटे, तेज और तकनीक के प्रति सचेत उद्यमियों की एक नई पीढ़ी पैदा हो गई है. और अब उन्हें मदद देने का वक्त आ गया है जिससे उन्हें परेशानी न हो."

इस घोषणा के साथ ही एक बार फिर निजी क्षेत्र में आस्था व्यक्त की गई है. उनके लिए उदारवाद की नीति घाटे का नहीं बल्कि फायदे का सौदा है. और अगर इससे भी कंपनियों में प्रतियोगिता तीखी होती है. तो फिर वे किस मुंह से शिकायत करेंगे?

—आनंद पी. रमन

"छोटे और तेज उद्यमियों की एक नई पीढ़ी आ गई है. उन्हें मदद देनी ही चाहिए"

आबिद हुसैन
सदस्य, योजना आयोग

"लाइसेंस नीति के पुराने और नए परिवर्तनों को जोड़कर देखने से यह बहुत बड़ी चीज लगती है"

बी.के. मोदी
अध्यक्ष, मोदी जेरॉक्स

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मद्रास

बदलता हुलिया

बड़े-बड़े बाजारों का निर्माण

मद्रास शायद जल्दी ही सिंगापुर का रूप ले लेगा. हाल तक दक्षिण भारत का यह उनींदा शहर अपनी विक्टोरियाकालीन वास्तुकला, एक या दो मंजिला इमारतों और लंबे-चौड़े बंगलों के लिए विख्यात रहा है. लेकिन धड़ाधड़ हो रहे निर्माण कार्यों से उसका नक्शा बदलना अब सुनिश्चित है. अगले तीन वर्षों में यहां शॉपिंग प्लाजा, शॉपिंग सेंटर और थोक बाजारों के निर्माण पर करीब 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे.

अगले तीन वर्षों में यहां के बड़े बाजारों के निर्माण पर करीब 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे. शहर का नक्शा बदलना तय है

मद्रास नगर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ए.एस. अहलूवालिया कहते हैं, "यहां का पूरा परिदृश्य ही बदल जाएगा." उनके मुताबिक शहर की भीड़भाड़ कम करने के लिए प्राधिकरण ने 1975 में इसके उपनगरों में नए शहरी केंद्र बनाने की जो योजना बनाई थी, उसी के अनुसार ये निर्माण हो रहे हैं.

मद्रास से 10 किमी की दूरी पर स्थित कोयमबेडु में नगर विकास प्राधिकरण 50 करोड़ रु. की लागत से 220 एकड़ क्षेत्र में फैला दुमंजिला व्यावसायिक कांप्लेक्स बना रहा है. यह कांप्लेक्स दो साल में तैयार हो जाएगा. इससे पुराने मद्रास के जॉर्जटाउन के पास कोतवाल चवाडी की गंदी सब्जी मंडी हट जाएगी. अहलूवालिया कहते हैं कि 3000 दुकानों वाले इस कांप्लेक्स में सब्जी, फल और फूलों का थोक बाजार होगा. करीब 800 से 1000 दुकानें कपड़े के थोक व्यापारियों को दी जाएंगी. 150 से 2400 वर्गफुट की दुकानों को 375 से लेकर 450 रु. प्रति वर्गफुट की दर से बेचा जाएगा. अधिकांश दुकानों की बुकिंग हो चुकी है. नगर विकास प्राधिकरण के वरिष्ठ नगर योजनाकार ए. लक्ष्मणन कहते हैं, "थोक बाजार में माल लादने-उतरने से होने वाली भीड़भाड़ जल्दी ही मद्रास शहर के लिए पुरानी बात हो जाएगी."

कोयमबेडु कांप्लेक्स इसका अकेला उदाहरण नहीं है. अगले साल के शुरू में शहर के 900 लोहा विक्रेता भी सत्तनगुडु के नए स्टॉकयार्ड में चले जाएंगे. यह जगह वैसे तो चिंगलपेट जिले में है पर मद्रास से इसकी दूरी मात्र 10 किलोमीटर है. प्राधिकरण 206 एकड़ सरकारी जमीन पर 15 करोड़ रु. की लागत से इस यार्ड का निर्माण कर रहा है. इतना ही नहीं, मद्रास के उत्तर-पश्चिम किनारे पर बसे माधवरम में भी 80 एकड़ जमीन पर तीन ट्रक टर्मिनल दो साल में तैयार हो जाएंगे. यहां 600 ट्रक ऑपरेटरों और 300 बुकिंग एजेंटों के रहने की व्यवस्था भी होगी. अहलूवालिया कहते हैं, "हम ट्रक और लारियों को शहर के बाहर ही रोक लेना चाहते हैं." इस योजना पर 10 करोड़ रु. खर्च होंगे.

श्याम टेकवानी

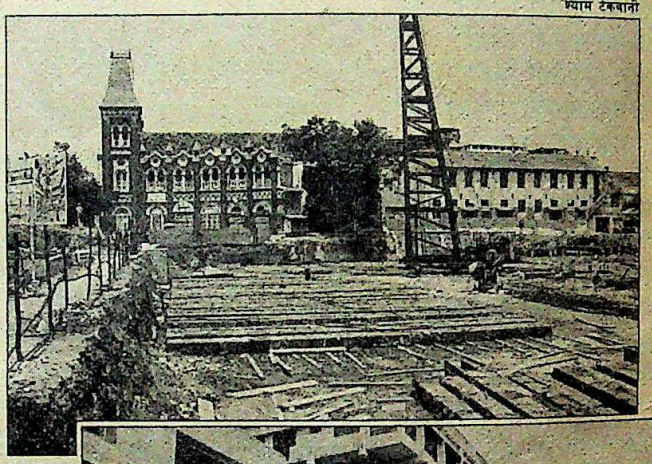

स्पेंसर का निर्माणाधीन तिमंजिला बाजार (ऊपर); और नया शॉपिंग सेंटर

अकेला मद्रास नगर विकास प्राधिकरण ही निर्माण के काम में नहीं लगा है. प्राइवेट कंपनियां भी काफी पैसा लगा रही हैं. 1989 के अंत तक सिंगापुर प्लाजा नामक विशाल छह मंजिला अत्याधुनिक शॉपिंग प्लाजा बनकर तैयार हो जाएगा. दोहरे आठ कोणों वाली यह भव्य इमारत पूरी तरह वातानुकूलित होगी और इसके फर्श पूरी तरह कालीन से ढके रहेंगे. इसकी ऊपरी मंजिल पर कांच की छत वाला एक रेस्तरां होगा. 20 लाख रु. की लागत से लगने वाला कंप्यूटरीकृत संगीतमय फव्वारा इसका खास आकर्षण होगा.

माउंट रोड पर स्थित नामी दुकान 'स्पेंसर' भी अगले पांच वर्षों में इसी व्यस्त इलाके की 10 एकड़ जमीन पर एक तीन मंजिला शॉपिंग कांप्लेक्स बनाने जा रही है. इस पर 50 करोड़ रु. खर्च होंगे. इसमें शीशे वाली पांच लिफ्टें, माल उतारने-चढ़ाने की 30 लिफ्टें, पांच प्रांगण, दूसरी मंजिल पर कार पार्किंग और छत पर 20,000 वर्गफुट में फैले मनोरंजन केंद्र के अलावा 600 दुकानें भी होंगी. इसकी तीनों वातानुकूलित मंजिलें कुल 5.5 लाख वर्गफुट जगह घेरेंगी.

स्पेंसर के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक आर. वेणुगोपाल बताते हैं कि इस कांप्लेक्स की सभी दुकानों और दफ्तरों को जोड़ने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज और क्लोज-सर्किट टीवी लगाने पर भी विचार हो रहा है. इसके अलावा वीरा प्रापर्टीज और अल्सा बिल्डर्स भी शॉपिंग कांप्लेक्स बना रहे हैं.

लेकिन क्या मद्रास में इतने बड़े-बड़े कांप्लेक्स चल भी पाएंगे? निर्माण कंपनी सौरभ एसोसिएट्स के साझीदार विजय गुलेछा कहते हैं, "शहर का विकास बहुत तेजी से हो रहा है. इतना हमने भी नहीं सोचा था." उनके अनुसार मद्रासवासी अब कपड़ों और बाहर खाने-पीने पर अधिक खर्च कर रहे हैं. स्पेंसर के वेणुगोपाल भी इतनी ही उम्मीद से भरे हैं, "पहले चरण की प्राय: सारी दुकानों की बुकिंग हो गई है और अभी भी इस बारे में पूछताछ करने वालों की बाढ़ रुकी नहीं है." अगर ये सारी उम्मीदें पूरी हो गईं तो शहर का नक्शा ही बदल जाएगा.

—एस.एच. वेंकटरमनी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आयातित कारें

भरपूर भंडार

नई नीति से कीमत घटेगी

क्या आप नाजुक-सी टोयोटा खरीदने के लिए येन जुटा चुके हैं? या मर्सिडीज की कीमत घटने के इंतजार में हैं? अगर आप विदेशी कार लेने की सोच रहे हैं तो कुछ दिन ठहर जाइए. चर्चा है कि अगले कुछ महीनों में करीब-करीब एकदम नई विदेशी कारों की भरमार हो जाएगी. और इनकी कीमतों में जबरदस्त कमी होगी.

वजह बहुत सीधी-सादी है. पिछले महीने सरकार ने एलान किया कि मुल्क लौटने वाले आप्रवासी भारतीय अपने साथ लाई विदेशी कारें बेच सकेंगे. अब उन्हें साथ लाई कार को दो से पांच वर्ष तक दुबारा न बेचने का बांड भरने से मुक्ति दे दी गई है. कुछ डीलरों का मानना है कि विदेशों में साल भर से भी ज्यादा वक्त बिताकर लौटे लोग अब गाड़ी लेकर ही आएंगे और लौटते ही उसे बेच डालेंगे.

निश्चित रूप से ऐसी कारों की मांग है. 1983 में कुछ समय के लिए इनकी पूछ घटने के बाद से कीमतें तेजी से बढ़ी हैं. एक नई 230 एसई मर्सिडीज कार यहां 18 लाख रु. तक में बिक सकती है. ढुलाई और सीमा शुल्क समेत इसे यहां लाने पर कुल कीमत 14 लाख रु. पड़ती है. होंडा एकॉर्ड 10 लाख रु. तक में बिकती है, जबकि इसे लाने में इसकी कीमत आठ लाख से अधिक नहीं होती. टोयोटा कोरोला भी सात लाख रु. में बिक जाती है. बाजार के एक जानकार का कहना है, "नई विदेशी कारों के लिए जबरदस्त भूख है."

यह भूख कब तक रहेगी, इस पर विवाद है. प्रमुख डीलर अजय बधवार कहते हैं, "20 लाख रुपए की कार कितने लोग ले सकते हैं?" तीन दशक से कारों की दुबारा बिक्री के धंधे में लगे भूपिंदर सिंह सूरी का कहना है, "कीमतें जरूर कम होंगी."

कुछ और लोगों का मानना है कि कई विदेशी गाड़ियां आने के बाद भी उनकी कीमतों में खास गिरावट नहीं आएगी. इस धंधे के सबसे बड़े लोगों में से एक ललित बागला को तो इस बात में ही संदेह है कि बाजार में कारों की भरमार होगी. वे कहते हैं कि कारों पर सीमा शुल्क इतना ज्यादा है कि विदेशों से लौटने वाले अधिकांश लोगों को इसे चुकाने में ही भारी दिक्कत होगी. वे कहते हैं कि इसके साथ ही सरकार दूसरे नियम भी कड़ाई से लागू करेगी. सरकार तमाम शुल्क वसूलने के साथ देखेगी कि कार आयात करने वाले ने विदेश में कार खरीदने लायक कमाई की भी है या नहीं.

सरकार की रणनीति भी यही है. वाणिज्य मंत्रालय के एक बड़े अधिकारी बताते हैं कि 1986 में सीमा शुल्क में (36 फीसदी तक की) वृद्धि के बाद आयातित कारें बेचने पर मुनाफा घट गया है. इसलिए बाजार फैलने पर मुनाफे का ज्यादातर हिस्सा सरकार की झोली में ही जाएगा.

वे बताते हैं कि सरकारी फैसला जिन तीन कारणों से लिया गया, उसमें मुनाफे में हिस्सा पाने का विचार भी एक था. दूसरा कारण था— आयातित गाड़ियों की दुबारा बिक्री में होने वाला प्रशासनिक झमेला.

तीसरी वजह यह है कि पाबंदी के बावजूद ज्यादातर आयातित कारों की बेनामी बिक्री हो जाती थी. इस व्यवसाय के लोगों के अनुसार बेनामी बिक्री का बाकायदा एक तंत्र विकसित हो गया है.

बागला जैसे डीलरों का मानना है कि सरकार अब इस मामले की खामियां दूर कर लेगी. इसलिए अब जो कारें आएंगी उन पर पूरा शुल्क अदा किया जाएगा. 1600 सीसी क्षमता से ऊपर की कारों पर 299 फीसदी और उससे छोटी कारों पर 224 फीसदी सीमा शुल्क चुकाना होता है. इसका बुरा असर भी दिखने लगा है. 1985-86 में 1060 कारों का आयात हुआ था जबकि 1986-87 में 847 और 1987-88 में मात्र 427 कारों का ही आयात किया गया.

इनमें से कई कारें दुबारा नहीं बिकतीं, इसलिए विदेशी कारों को लाने-बेचने का ज्यादा काम राज्य व्यापार निगम ही करता है. राजनयिकों की पुरानी कारों पर तो निगम का ही एकाधिकार है. निगम अवक्षयण की तयशुदा दरों पर उन्हें खरीदकर खुली निविदा के जरिये उनकी बिक्री करता है. निगम हर साल 600 कारें बेचता है पिछले महीने निगम के अधिकारी, सरकारी घोषणा से कीमत गिरेगी, इस अंदेशे से परेशान होकर निविदा के जवाबों का इंतजार कर रहे थे. लेकिन एक अधिकारी ने बताया कि निविदा भरने वालों ने सामान्य दरों पर ही खरीद के प्रस्ताव रखे हैं. और बाजार में कोई खलबली नहीं है.

लेकिन यही बात निगम के अफसर और डीलर अक्सर कहते रहे हैं. वैसे आजकल उनकी जुबान पर एक नया जुमला है, "देखिए आगे क्या होता है." बाजार का रुख भी फिलहाल ऐसा ही है. —डेविड देवदास

बिक्री के लिए रखी कारें

भवान सिंह

आयात संबंधी नियमों में छूट के बाद आयातित कारों की भरमार हो जाने की संभावना है. लेकिन सवाल यह है कि क्या इन कारों के लिए लंबे समय तक मांग बनी रहेगी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शेयर बाजार

उत्साह बरकरार

नई घोषणाओं से जान लौटी

शेयर बाजार में उत्साह का माहौल पिछले पखवाड़े भी बना रहा. वैसे अधिकारियों ने शेयरों की खरीद बढ़ते जाने से परेशान होकर पड़ते की मात्रा बढ़ाकर यह उफान रोकने की कोशिश की. लेकिन इसका असर भी नहीं पड़ा. केरल वगैरह में मानसून के समय से पूर्व पहुंचने की खबर ने इस उम्मीद को मजबूत किया कि इस बार मानसून अच्छी होगी जिसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा.

सट्टेबाजी के लिए खरीद के अंदेशे में ये कदम उठाए गए थे, पर इनका बहुत ही कम असर हुआ. सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी, एसीसी में अनिश्चितता का दौर बना हुआ है और इस बीच उसके शेयर चढ़ते ही जा रहे हैं. पिछले पखवाड़े वे 254 रु. तक पहुंच गए. रिलायंस और टिस्को जैसे शेयर 3 जून को 216 रुपए और 887.50 रुपए के नए

चार्ट: बी के शर्मा

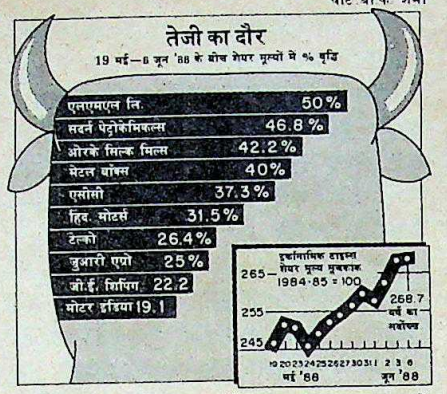

उच्चतम स्तर पर पहुंचे. मगर 6 जून को सप्ताह शुरू होते ही वे क्रमशः 205 और 850 रुपए पर आकर खुले.

लेकिन यह मामूली गिरावट बाजार की मंदी के कारण नहीं, बल्कि अपने स्वाभाविक संतुलन की प्रक्रिया के कारण थी. वित्तीय संस्थाओं ने खरीदने की जगह शेयर उतारना शुरू कर दिया है लेकिन इससे भी बाजार का उत्साह मंद नहीं पड़ा.

बाजार का उत्साह इकॉनॉमिक टाइम्स शेयर मूल्य सूचकांक में भी प्रतिबिंबित हो रहा है जो 20 मई के 251.7 से बढ़कर पिछले पखवाड़े 268.4 पर पहुंच गया था. नामी शेयरों के साथ कम विख्यात शेयर भी चढ़ने लगे हैं. आंध्र सीमेंट, भारत फोर्ज, सिएट टायर्स, इंडरॉल, काइनेटिक होंडा, अल्फा लावेल, श्रीराम फाइबर्स और पोंड्स इंडिया भी पिछले पखवाड़े चढ़े. पिछले साल अब तक के सबसे बड़े, 519 करोड़ रुपए के इश्यू जारी करने वाली रिलायंस भी एक बार और बाजी लगाने का फैसला कर चुकी है. उसके लिए इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता था.

बाजार के बढ़ते जाने का एक और कारण सरकार की ओर से हुई कुछ नई घोषणाएं हैं. इसमें सीमा शुल्क की वापसी की मात्रा बढ़ाना (जिससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा), लाइसेंस नीति को और उदार करना (खास तौर पर विदेशी पूंजी वाली योजनाओं के लिए) और निवेश भत्ते को फिर से चालू करना शामिल हैं.

विदेशी पूंजी को आकर्षित करने की कोशिश कर रही सरकार के लिए जरूरी है कि शेयर बाजार की हालत अच्छी रहे. इन सबके साथ ही अच्छे मानसून की उम्मीद तथा टेल्को और टिस्को के अच्छे परिणाम की घोषणा की आशा से बाजार में और उफान आ रहा है. लगता हैं निराशा वाले दिन आखिरकार समाप्त हो गए.

जमा स्टॉक

	1988 ऊंचा	नीचा	बंद 6.6.88	पखवाड़े में स्थिति
अशोक लेलैंड	40.00	30.25	39.25	3.25 +
एसोसिएटेड सीमेंट	254.00	128.50	254.00	61.00 +
एटलस कोप्को	63.50	33.50	56.00	5.50 +
एशियन पेंट्स	170.00	128.75	168.75	8.75 +
बजाज ऑटो	520.00	187.50	203.75	3.75 +
बड़ौदा रेयॉन	282.50	140.00	245.00	15.00 —
बाटा इंडिया	71.50	50.50	64.75	2.75 +
भारत फोर्ज	146.00	101.00	146.00	15.00 +
बिरला जूट	45.00	32.25	45.00	9.25 +
ब्लो प्लास्ट	125.00	28.00	42.00	1.00 +
बॉम्बे डाइंग	146.00	101.00	146.00	15.00 +
ब्रिटानिया इंडिया	109.00	75.00	91.00	7.00 +
ब्रुक बांड	98.00	75.00	93.50	2.50 +
सीएट टायर्स	88.00	55.00	60.00	—
सेंचुरी स्पिनिंग	875.00	617.50	857.50	12.50 —
क्लोराइड इंडिया	80.50	59.00	69.50	0.50 —
कोलगेट	220.00	160.00	218.30	18.30 +
सायनामिड	52.00	33.00	51.00	1.00 —
डीसीएम	47.00	28.00	44.00	10.00 +
डनलप	83.50	69.50	81.00	9.50 +
ईआई होटल्स	54.00	38.00	51.00	—
एस्कार्ट्स	57.00	37.00	53.50	7.50 +
फिनोलेक्स केबिल्स	415.00	272.50	408.75	68.75 +
फूड स्पेशिलिटीज	142.00	93.50	135.00	9.00 +
गरवारे नाइलोन	41.50	20.00	40.00	1.00 +
जी.ई. शिपिंग	33.00	20.80	33.00	5.15 +
गुजरात स्टेट फर्टि.	138.00	75.00	138.00	21.50 +
ग्रासिम इंडिया	104.75	81.50	104.50	12.00 +
हिंदुस्तान सिबा	520.00	332.50	480.00	10.00 —
हिंदु. एल्यूमिनियम	139.00	73.00	87.00	10.50 +
हिंदुस्तान कोकोआ	215.00	67.50	86.50	2.75 +
हिंदुस्तान लीवर	81.00	59.50	74.00	1.00 +
हिंदुस्तान मोटर्स	26.30	15.80	26.30	5.70 +
आई.ई.एल	43.75	31.00	41.25	0.75 +
इंडियन आर्गेनिक	27.00	15.00	26.50	1.00 +
इंडियन रेयॉन	67.50	46.00	66.00	1.50 +
इंड्रोल	223.75	133.75	180.00	12.50 +
इंगरसॉल-रैड	335.00	205.00	285.00	5.00 —
आई.टी.सी.	46.00	30.00	44.50	4.25 +
जे.के. सिंथेटिक्स	69.00	45.50	68.00	3.00 +
काइनेटिक इंजी.	225.00	161.25	225.00	35.00 +
किर्लोस्कर न्यूमिस	59.00	48.00	55.00	4.00 —
केएसबी पम्प्स	425.00	215.00	285.00	5.00 +
लारसन-टुब्रो	97.00	75.50	97.00	2.50 +
लिप्टन	67.00	52.00	65.50	4.50 +
लोहिया-मशीन्स	20.00	9.00	19.50	5.50 +
मदुरै कोट्स	77.00	59.00	69.50	2.25 —
महिंद्रा-महिंद्रा	63.00	48.50	60.00	—
मोटर इंडस्ट्रीज	630.00	447.50	622.50	97.50 +
मुकुंद आयरन	97.00	72.50	96.00	3.00 +
नेशनल आर्गेनिक	525.00	390.00	475.00	5.00 +
निरलॉन	16.00	5.00	13.00	—
ओरके सिल्क मिल्स	50.50	17.00	50.50	12.50 +
ओटिस एलिवेटर	215.00	161.25	195.00	7.50 +
पेइको इलेक्ट्रॉनिक्स	35.00	24.50	34.50	1.50 +
फाईजर	79.50	50.00	68.00	4.00 —
प्रीमियर ऑटो	37.50	23.00	36.50	3.00 +
रैनबेक्सी	117.50	76.00	112.50	10.50 +
रेमंड	96.00	41.50	50.50	2.00 +
रॉकिट ऐंड कोलमैन	219.00	175.00	216.00	22.00 +
रिलायंस इंडस्ट्रीज	213.00	69.00	213.00	49.00 +
शॉ वैलेस	132.00	50.50	59.00	5.00 +
सीमेन्स इंडिया	80.00	56.00	72.00	6.00 —
श्रीराम फाइबर्स	57.00	32.50	55.00	9.25 +
एसकेएफ बैयरिंग्स	1365.00	1058.00	1325.00	50.00 +
स्पिक	58.50	23.50	58.00	10.00 +
टाटा स्टील	887.50	568.75	875.00	125.00 +
टेल्को	675.00	340.00	670.00	130.00 +
वाम आर्गेनिक	101.00	75.00	101.00	3.00 +
विम्को	24.00	11.00	16.00	0.50 —

भारतीय रुपए का मूल्य

देश	मुद्रा	इकाई	टिकी मूल्य (रुपए में)	क्रय मूल्य (रुपए में)
आस्ट्रेलिया	डालर	1	11.0800	10.9648
आस्ट्रिया	शिलिंग	1	1.1324	1.1199
बहरीन	दीनार	1	34.9332	34.8996
बांग्लादेश	टका	100	42.9713	42.9086
कनाडा	डालर	1	11.1478	11.0296
डेनमार्क	क्रोना	1	2.0885	2.0662
मिस्र	पौंड	1	9.6332	9.5817
फ्रांस	फ्रैंक	1	2.3980	2.3391
हांगकांग	डालर	1	1.7575	1.7394
इंडोनेशिया	रुपिया	100	0.0760	0.0750
ईरान	रियाल	100	19.5732	19.5001
इटली	लीरा	100	1.0636	1.0010
जापान	येन	100	11.10	10.70
केन्या	शिलिंग	1	0.7599	0.7136
कुवैत	दीनार	1	48.0560	47.9192
मलेशिया	डालर	1	5.3210	5.2627
मारीशस	रुपया	1	1.0260	1.0000
नेपाल	रुपया	1	0.6092	0.5790
हालैंड	गिल्डर	1	7.0860	7.0101
पाकिस्तान	रुपया	1	0.7560	0.7030
सिंगापुर	डालर	1	6.7967	6.7174
स्पेन	पेसो	1	0.1190	0.1086
श्रीलंका	रुपया	1	0.4290	0.4080
स्वीडन	क्रोना	1	2.2778	2.2534
स्विट्जरलैंड	स्विस फ्रैंक	1	9.5457	9.4418
तंजानिया	शिलिंग	1	0.1890	0.1700
थाईलैंड	बहत्त	100	52.9001	50.0003
ब्रिटेन	पौंड	1	24.5761	24.4409
सं. राज्य अमेरिका	डालर	1	13.1363	13.5762
सं. अरब अमीरात	दिरहाम	1	3.5900	3.5532
सोवियत संघ	रूबल	1	16.3469	16.2830
पश्चिम जर्मनी	जर्मन मार्क	1	8.1037	7.9999

स्रोत—बैंक ऑफ टोक्यो, नई दिल्ली, 6.6.88

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जब खुशी बाँटने की घड़ी आये, खुशी का मज़ा दुगुना हो जाये.

"हसीन एचएमटी!"

hmt घड़ियां
राष्ट्र के समय प्रहरी

HTA 8604

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

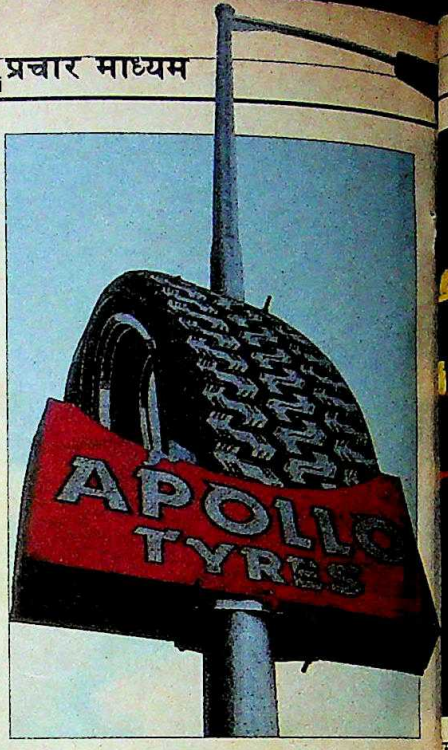

विज्ञापनबाजी के करिश्माई नमूने: परदे और टायर का इस्तेमाल

विज्ञापन

चप्पे-चप्पे पर चस्पां प्रचार

विज्ञापनबाजी के कारोबार में नई तकनीक और शैली का समावेश

कहा जाता है कि पानी अपना सतह खुद ढूंढ़ लेता है. विज्ञापनबाजों का भी कुछ ऐसा ही मामला है. वे विज्ञापनबाजी के लिए जगह बना ही लेते हैं. जगह उनके लिए कोई समस्या नहीं. विज्ञापनबाजों का मक्का-मदीना बंबई इसका प्रमाण है. इस शहर का चप्पा-चप्पा जैसे विज्ञापनों से पट गया है. बसों के तीनों तरफ, स्कूटर में पीछे लगे चक्के पर, नौकाओं के पालों पर, गुब्बारों पर, पेड़ों की डालियों पर, हवाई अड्डों में वाहक पट्टियों और यहां तक कि क्रिकेट खिलाड़ियों के शरीर पर हर जगह विज्ञापनों का बोलबाला है. और संभावनाएं अनंत हैं.

कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी जा रही. जहां भी गुंजाइश दिखी वहीं टांग दिया एक बोर्ड. विज्ञापनबाजी का यह तरीका जिसे 'आउट-डोर' विज्ञापन कहा जा सकता है, काफी सस्ता है और फिर इसके जरिये उपभोक्ताओं को अपने सामान की याद बार-बार दिलाना आसान भी होता है. विज्ञापन एजेंसी 'लिंटास' के मीडिया प्लानिंग सेल के सह-निदेशक हेलेन अंचल ने कहा, "दीवारें भरती जा रही हैं. लिहाजा वे नई दीवारें तलाश रहे हैं. टीवी और रेडियो के बाद घर के बाहर की जगहें ही इस दशक का माध्यम होंगी." पूरी बंबई जैसे पुरचून की विशाल दुकान बन गई है जहां हर जिंस जैसे चीख रही है, 'मुझे खरीदो, मुझे खरीदो.' विज्ञापन एजेंसी 'त्रिकाया' के क्रिएटिव डायरेक्टर क्रिस्टॉपर डी. रोजारिओ ने कहा, "दिलचस्प बात है यह जिस किसी भी नई जगह पर ट्रैफिक एक बार जाम हो गया, वहीं विज्ञापन के चार-पांच बोर्ड लटक जाते हैं."

एक समय था जब केवल साबुन या टायर के सीधे-सादे विज्ञापन होते थे, कुछ इस तरह के, "कृपया हमें खरीदें, हम आपके परिवार के लिए ठीक हैं." आज हालत यह है कि आउटडोर विज्ञापन किसी भी चीज का हो सकता है—चाहे वह नए शेयरों की सूचना हो या जौहरी, खुदरा व्यापारी, कसाई, बेकर और मोमबत्ती बनाने वाले के सामान की हो. संदेश भी पहले की तरह सरल नहीं रह गए हैं. अब वे छेड़ते हैं, लुभाते हैं और दर्शक हक्का-बक्का रह जाता है. एक फिल्मी पत्रिका 'गोविंदा और किमी की गैरकानूनी करतूत' देखने के लिए आमंत्रित करती है तो एक जौहरी अपने शोरूम के बाहर एक नाव में विज्ञापन पताका फहराता है.

और इसमें कमाई भी खूब है. यदि कोई कंपनी बंबई के सारे विज्ञापन बोर्डों पर कब्जा करना चाहे तो उसे हर महीने 8 करोड़ या इससे भी अधिक रुपए खर्च करने पड़ेंगे. पूरे शहर में आज लगभग 4,000 विज्ञापन बोर्ड लटके हैं. इनके किराए इलाके के आधार पर तय होते हैं. गए-बीते इलाके में एक विज्ञापन बोर्ड पर हर महीने 10,000 रुपए खर्च हो सकते हैं तो बेहतरीन इलाके में 10 दिनों के लिए 60,000 रु. देने पड़ सकते हैं.

अब तो विज्ञापन के लिए नई-नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है. बिजली ने इस काम को और अधिक आसान बना दिया है. इसकी मिसाल है बंगलूर में बनाया गया एक नया विज्ञापन बोर्ड, जो बंबई में भी जल्दी ही

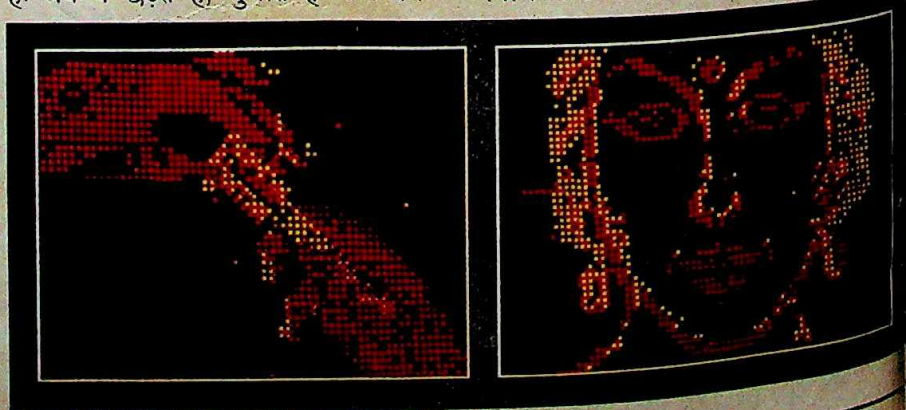

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

फूटी और अमूल के विज्ञापनः अनंत संभावनाएं

खने को मिलेगा. यह विज्ञापन इस प्रकार —एक अंधेरे बोर्ड पर पहले लाल प्रकाश में ींची गई एक पेंसिल चमकती है, फिर वह सिल दाहिनी आंख बनाती है और फिर यीं. इसके बाद नाक और होंठ बनाती है. फिर बोर्ड अंधेरे में डूब जाता है और अचानक रा चेहरा लक्मे काजल के साथ चमकने गता है. यह न तो नियोन है और न ही लेक्ट्रॉनिक विज्ञापन. यह एक बहुरंगी सजीव जाइन बोर्ड (एमएडी) है जोकि बिलकुल या है. यह बीकॉन प्लास्ट के बोबो भसीन के माग की उपज है. वे कहते हैं, "यह है ापके लिए इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन. इसमें टिलता नाम की कोई चीज नहीं है. यह ोधा आपकी आंखों में समा जाता है."

'दाकुन्हा' नामक विज्ञापन एजेंसी तो निथ कंप्यूटरों के लिए एक भारी-भरकम वोट के साथ मैदान में उतर पड़ी. इस वोट को जब सड़कों पर ले जाया गया तो पाहियों ने इसे दो बार पकड़ लिया. वे पकी फ्लैशिंग लाइट और विचित्र आवाज

सजीव विज्ञापनः असरदार

को समझ ही नहीं सके थे. वह दिन दूर नहीं जब आउटडोर विज्ञापन होलोग्राम या तकनीक के जरिये किए जाएंगे. यह तकनीक हवा में जादुई त्रि-आयामी (थ्री-डी) असर पैदा करेगी. इसके बारे में रोजारिओ बड़े भयावह ढंग से बताते हैं, "आप यह सोचेंगे कि मैं यहां बैठा हूं. लेकिन ऐसा होगा नहीं, वह मेरा होलोग्राम होगा."

तकनीक तो फरेब है. दरअसल यह बहुत सृजनात्मक नहीं है. इसका सहारा तो वे सुस्त लोग लेते हैं जो बहुत सोच-विचार नहीं कर सकते. यह बेहतरी नहीं बल्कि विशालता, चमक और शोर का पर्याय है. वैसे, समझदारी भरे विज्ञापन भी चल रहे हैं. एअर इंडिया (नाश्ता फ्रैंकफुर्त में) या अमूल (भरतनाट्यम-यम-यम) के विज्ञापन इसकी मिसाल हैं. या अभी हाल की फूटी को ले लीजिए. इसका देश भर में इस तरह प्रचार किया गया मानो भारत में इसके सिवा आम बचा ही न हो. जब यह बाजार में आया तो फूटी कन्या मालविका तिवारी के चित्र देश भर में विशाल विज्ञापन बोर्डों पर लगा दिए गए और बंबई में आम के पेड़ों पर फूटी के चमकते चौकोर डिब्बे लटका दिए गए.

किटप्लाई ने तो हाल में बंबई में एक विज्ञापन बोर्ड पर एक आलमारी ही लगा दी. मकसद यह बताना था कि किटप्लाई पर किसी भी मौसम का असर नहीं होता. कुछ समय पहले टायर कंपनी डनलप ने मनमौजी ट्रक ड्राइवरों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के आसपास के कई दर्जन ढाबों को अपना लिया. और गिलासों, बर्तनों, बेयरों की बनियानों पर भी डनलप के विज्ञापन चिपका दिए गए. क्रिकेट का मौसम विज्ञापन के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है. विज्ञापनबाजों ने क्रिकेट खिलाड़ियों को तो विज्ञापनों का चलता-फिरता बोर्ड ही बना दिया है.

लेकिन देश में सबसे ज्यादा चर्चित विज्ञापन अभियान अमूल का है. गुजरात के एक छोटे अनजान सहकारी समिति का मक्खन आज देश का सबसे प्यारा मक्खन बन गया है. इसके विज्ञापन अभियान ने सिद्ध कर दिया है कि आउटडोर विज्ञापन कितना कारगर हो सकता है. 'आरे एडवरटाइजिंग' के एक अधिकारी ने कहा, "अमूल अच्छी तरह जान गया है कि मक्खन कहां और कैसे लगाना है." 'दाकुन्हा एसोसिएट्स' के चीफ एक्सक्यूटिव भरत डाभोलकर बताते हैं कि किस तरह उनकी कंपनी ने इस अभियान को सफल बनाया, "विज्ञापन में मक्खन के बारे में लंबा-चौड़ा नहीं हांका गया. बल्कि लोगों को सोचने पर विवश कर दिया गया." पिछले साल जब इस मक्खन का पैक बदला गया तो 'दाकुन्हा' ने अमूल बेबी का एक पांच फुट का

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अब मशहूर रंगीन टी वी की दुनिया में

चैम्पियनों का चैम्पियन

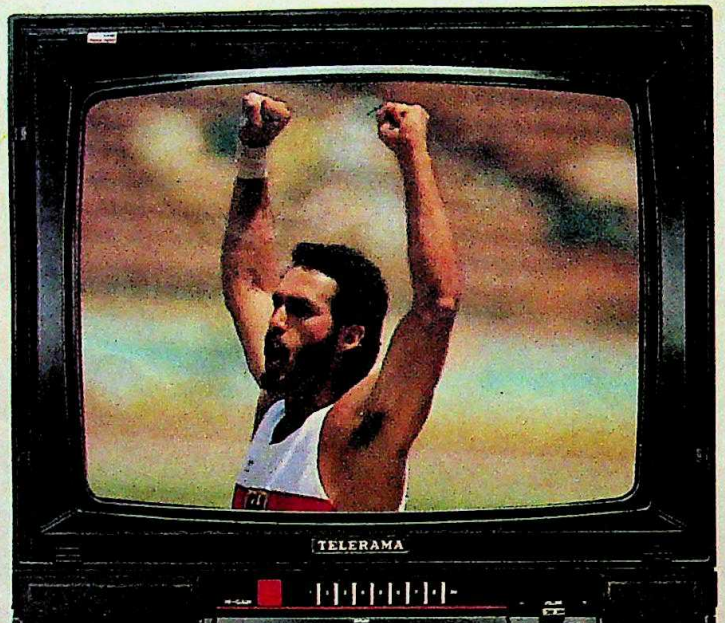

TELERAMA
MAGNUM DX HI-GAIN

दो साल की गारंटी पिक्चर ट्यूब सहित

नवीनतम अन्तर्राष्ट्रीय रूप। सम्पूर्ण काला और फिनिश चिकनी। हू-ब-हू रंग सहित जीवन्त तसवीर। दो-तरफा स्पीकर—जिसमें क्रॉसओवर नेटवर्क तकनीक की वजह से आवाज़ भी जानदार। कम्प्यूटर की मदद से तैयार, इसलिए काम की क्वालिटी लाजवाब और निर्भरयोग्यता की भी पूरी निश्चयता। दूर हो या पास-हाई-गेन की देन स्पष्ट और शानदार तसवीर। मैगनम DX यूरोकलर टी वी—देखने में आराम, रखने में शान।

टेलेरामा मैगनम DX हाई-गेन टी वी। यकीन कीजिये—यही है चैम्पियनों का चैम्पियन!

It's the smart choice

HTA-3337A2

अपने करीबी डीलर के पास इसके दमखम की जाँच कीजिये...
सचमुच, यह सबको मात देगा।

TELERAMA AUTHORISED SERVICE CENTRE FOR ITT COLOUR TVs

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नामस भोजानी

जनहित के विज्ञापन: रचनात्मक पहल

पुतला बनाया, उसके लिए कपड़े सिलवाए, जूते खरीदे, सिर पर बाल लगाए और फिर उसे विज्ञापन बोर्ड पर लगा दिया. उसके सामने लिखा था, "यह मेरा नया पैक है."

चौकोर डिब्बे वाले पेयों के विज्ञापन में तो 'दाकुन्हा एसोसिएट्स' एक कदम और आगे बढ़ गया. उसने एक आदमी को चार फुट के व्यास वाले गोलमटोल कपड़े पहनाकर 'मिस्टर रीयल' के नाम से सड़क पर उतारा. बाद में उसकी तस्वीरों के साथ अखबार की खबर जैसा विज्ञापन बना दिया "क्या यह विज्ञापन का करतब है?" कुछ दिनों बाद दूसरी रिपोर्ट आई, "मिस्टर रीयल फिर देखे गए." ऐसे दस मिस्टर रीयल अब विभिन्न शहरों में घूमते हैं.

विज्ञापनों के नारे निश्चित रूप से छल्लेदार होते जा रहे हैं. और मॉडल अधिक सेक्सी. डाभोलकर कहते हैं, "मॉडल कानून की तरह होती हैं. उनमें आपकी अपनी संस्कृति का अक्स होना जरूरी है." दस साल पहले बिना बांह की ब्लाउज पहने मॉडल को अच्छा नहीं माना जाता. विज्ञापन के नारे भी पहले की बनिस्बत अधिक चुस्त और चुलबुले होते जा रहे हैं. देश में विज्ञापनबाजी में अगुआ बंबई शहर है. दिल्ली और बंगलूर जैसे दूसरे शहर भी इस होड़ में शामिल हैं लेकिन वे बंबई के मुकाबले बहुत पीछे हैं.

फिलहाल धूम्रपान विरोधी अभियान जोरों पर हैं—'धूम्रपान न करने वाले का चुंबन लेकर अलग ही किस्म का आनंद लीजिए'. दिल्ली और चंडीगढ़ में विज्ञापन बोर्डों के आकार-प्रकार के कड़े नियम हैं, लेकिन बंबई में मैदान खुला हुआ है. यह एक तरह की सड़क कला दीर्घा है.

चमकदार विज्ञापन बोर्डों के बढ़ने से उन एजेंसियों की भी बन आई है जो ऐसे विज्ञापन बोर्ड बनाती और भाड़े पर देती हैं. पिछले दशक में आउटडोर विज्ञापन का कारोबार आर्थिक नजरिए से लगभग सात गुना बढ़ा है. बंबई की सबसे बड़ी विज्ञापन कंपनियों में से एक 'आरे' के एक अधिकारी ने कहा, "विज्ञापन बोर्डों पर विज्ञापन करने से बिक्री बढ़ रही है और लोग अधिक खरीदारी कर रहे हैं." बंबई में आज ऐसी लगभग 40 कंपनियां हैं जो हल्की रोशनी, कई तरह के बोर्ड, पेंटर आदि देने की पेशकश करती हैं. ये पेंटर छह घंटे के भीतर पूरी जगह को रंग डालते हैं.

हवाई अड्डा क्षेत्र विज्ञापन बोर्डों से अटा पड़ा है. बंबई के दोनों हवाई अड्डों पर विज्ञापन करने का एकाधिकार-सा 'आरे' को मिला है. 'आरे' की वीणा सद्रांगनी ने कहा, "हमने तीन महीने में 90 फीसदी जगह बेच डाली." भारत में यह पहला मौका है कि इस शहर के हवाई अड्डे के एअरबस प्रस्थान लाउंज में एरिस्टोक्रेट वालों ने 'एरिस्टोगैग्स' खिड़की बनाई है जो चुटकले सुनाती है. इसके पीछे विचार यह है कि विमान हमेशा देर से आते हैं लिहाजा लोगों को समय काटना ही पड़ता है. तो क्यों न चुटकले सुनें. इन चुटकलों के निर्माता रोजारिओ के मुताबिक इनमें ऐसे चुटकले हैं जिन्हें सुनकर एरिस्टोक्रेट के बारे में लोगों की धारणा अच्छी बनेगी. इन चुटकलों के कुछ नमूने ये हैं.

ग्राहक: "बेयरा, मेरे सूप में एक मक्खी है."
बेयरा: "ओह सर, उसके 10 रु. अलग से."
ग्राहक: "बेयरा, मेरे सूप में एक तेलचट्टा है."
बेयरा: "हां सर, मक्खी छुट्टी पर है."
ग्राहक: "सूप में मक्खी क्या कर रही है?"
बेयरा: "मेरे विचार से तैर रही है, सर."
ग्राहक: "मेरे सूप में एक मेंढक है."
बेयरा: "क्षमा करें, सर, सूप में तो आम तौर पर मक्खी होती है."

—सिमरन मार्गव, बंबई में ब्यूरो रिपोर्टों के साथ

हवाई अड्डे पर विज्ञापनबाजी

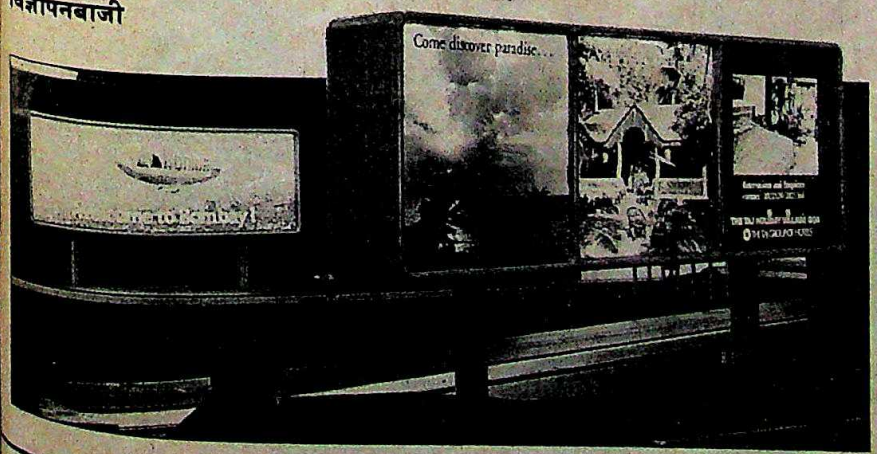

HTA-3337A2

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गुलबादीन हिकमतियार

'चुनी हुई सरकार ही चाहिए'

पिछले आठ वर्षों से पाकिस्तान में रहकर अफगान मुजाहिदीनों की अगुआई करने वाले 40 वर्षीय गुलबादीन हिकमतियार किसी बागी संगठन के अगुआ नहीं लगते. लाल-लाल गाल और काली पगड़ी में वे सौम्य अयातुल्लाह दिखते हैं. मुजाहिदीनों के सात दलीय गठबंधन के अगुआ हिकमतियार सोवियत फौजों की वापसी के साथ दो तरह से एक प्रमुख हस्ती के रूप में उभरे हैं. एक, नजीबुल्ला विरोधी के रूप में और दूसरे, अफगानिस्तान की सत्ता पर नियंत्रण के लिए मुजाहिदीनों के भीतर चलने वाले संघर्ष के कारण. अमेरिका और उनके पाकिस्तानी मेजबान राष्ट्रपति जिया-उल-हक दोनों चाहते हैं कि अफगानिस्तान की बागडोर इस 40 वर्षीय युवा इंजीनियर के हाथों में हो. विशेष संवाददाता ***रमिंदर सिंह*** *ने पिछले पखवाड़े पेशावर के शरणार्थी शिविरों और मुजाहिदीनों के सुरक्षित अड्डों पर पांच घंटे तक चक्कर लगाने के बाद उनसे एक घंटे तक बातचीत की. उसी के कुछ अंश:*

● ***आने वाले महीनों में अफगानिस्तान में कितनी शांति रह पाएगी? देश के अंदर और बाहर सक्रिय मुजाहिदीन गुट एक होकर सरकार बनाने में क्या कामयाब हो पाएंगे?***

रूस ने अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी शुरू कर दी है. उनके हटने के बाद नजीब सरकार चल नहीं पाएगी. नजीब सरकार रूसी सेना के पूरी तरह हटने के पहले भी गिर सकती है. हम चाहते हैं कि मुक्त हुए क्षेत्र की किसी सुरक्षित जगह में जल्दी ही एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाए.

● ***कब तक?***

कुछ हफ्तों के अंदर ही. हमने जगह का चुनाव कर लिया है. पर उसके बारे में अभी किसी बाहरी को न बताने का फैसला किया है. हम सभी प्रांतों के लिए गवर्नर और जिलों के लिए सब-गवर्नर नियुक्त करेंगे और किसान मोर्चों के कमांडरों के स्थानीय परिषदों का गठन करेंगे. आप भी जानते हैं कि मुजाहिदीन और रूसियों के बीच आठ साल से लड़ाई चल रही थी. नजीब की कोई भूमिका ही नहीं रह गई थी. रूसी फौजों के हट जाने के बाद यह लड़ाई बंद हो जाएगी और हमारे मुल्क में शांति कायम हो जाएगी.

● ***मुजाहिदीनों के खिलाफ लड़ने वाली अफगान सेना में भरती अफगान लोगों का क्या होगा?***

हमने उन सभी लोगों के लिए आम माफी की घोषणा की है जो पिछले आठ वर्षों में रूसियों का समर्थन करते रहे. लेकिन इसके लिए उन्हें अपने देश लौटना, इस्लाम और अपने लोगों के प्रति वैर भाव छोड़ना तथा अपने इलाके से रूसी फौज के हटने के चार हफ्ते के अंदर मुजाहिदीनों की जमात में शामिल होना होगा.

● ***क्या संगठन के दूसरे लोग उन पर शक नहीं करेंगे?***

हम विशेष कार्ड जारी करेंगे. मुजाहिदीनों को नुकसान पहुंचाना उनके लिए मुश्किल होगा. इस आम माफी से रोज बड़ी संख्या में लोग संगठन में शामिल हो रहे हैं.

● ***आपने कहा है कि आप जेनेवा समझौते को नहीं मानते?***

समझौते में कहा गया है कि रूसी फौज नौ महीने में वापस होगी. यह बात हमें मंजूर नहीं. हमने नौ महीनों की जगह तुरतफुरत और बिना शर्त वापसी की मांग की थी.

● ***क्या यह वापसी बिना शर्त नहीं है?***

नहीं. रूसी सेना की वापसी तो कई चरणों में होने वाली है. रूसी लोग अपने पीछे नजीब सरकार को स्थापित कर जाना चाहते हैं. हम लोग समझौते की बातचीत में शामिल नहीं थे. जेनेवा में अफगानों का प्रतिनिधित्व किसी ने भी नहीं किया इसलिए हम इस समझौते को मानने के लिए कतई मजबूर नहीं हैं.

रमिंदर सिंह

CC-0. In Public Do... Haridwar...

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

• क्या मुजाहिदीनों को जानबूझकर बाहर रखा गया?

हां. रूसी यही चाहते थे.

• आपकी बात रखने वाले पाकिस्तान और अमेरिका तो वहां थे ही. उनके बारे में आपकी क्या राय है?

पाकिस्तान चाहता था कि किसी तरह रूसी फौज की वापसी का समझौता हो जाए. इसलिए उसने समझौते पर दस्तखत किए.

• भावी अंतरिम सरकार में आप अपनी भूमिका क्या मानते हैं?

हमने एक अंतरिम मुजाहिदीन इस्लामी राज्य की घोषणा की है. इसके नेतृत्व के लिए

यूएनआई/एएफपी

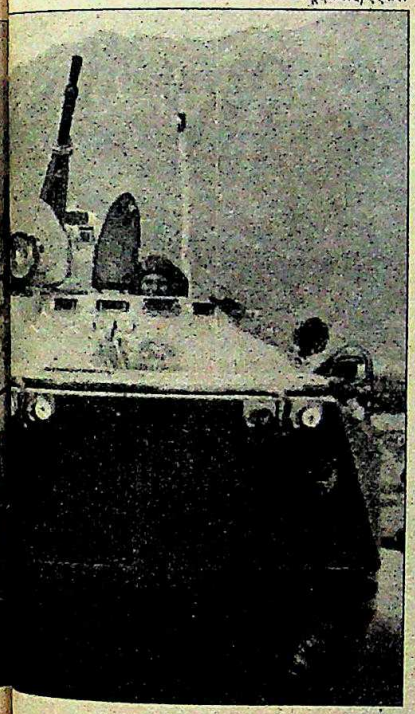

अफगानिस्तान से सोवियत फौजों की वापसी; और (बाएं) मुजाहिदीनों के प्रमुख हिकमतियार

सर्वोच्च परिषद बनाई गई है जिसके पास राष्ट्रपति वाले अधिकार होंगे. मैं भी इस परिषद का सदस्य हूं.

• क्या सरकार में आपकी कोई भूमिका नहीं होगी?

सरकार इसी परिषद के मातहत चलेगी. परिषद के पास सबसे अधिक ताकत है.

• आपने अपने भाषणों में राष्ट्रपति नजीबुल्ला की भारत यात्रा और अफगान समस्या में भारत की भूमिका की आलोचना की है.

हमें उम्मीद नहीं थी कि अफगान मसले में भारत की भूमिका इतनी उलटी होगी. बदकिस्मती है यह. भारत खुद को निर्गुट आंदोलन का संस्थापक सदस्य बताता है फिर भी वह अफगानिस्तान पर विदेशी मदद के सहारे थोपी गई कठपुतली सरकार का समर्थन करता है. भारत ने पिछले 10 वर्षों तक चुप्पी साधे रखी और कभी रूसी हमले के खिलाफ नहीं बोला. रूसियों ने हमारे 13 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया. अफगानों की सही लड़ाई का समर्थन करने की जगह भारत ने नजीब की कठपुतली सरकार को समर्थन दिया. ऐसा सिर्फ क्रेमलिन को खुश करने के लिए किया गया.

• अगर मुजाहिदीन अफगानिस्तान में सत्ता में आते हैं तो आप भारत-अफगानिस्तान के बीच कैसे संबंध चाहेंगे?

भारत 10 वर्षों तक चुप रहा और उसने कभी रूसी हमले का विरोध नहीं किया. उसने अफगान कौम के समर्थन के बजाय रूस को खुश करने के लिए नजीब की कठपुतली सरकार का समर्थन किया

हम भारत के साथ अच्छे संबंध और अपने तमाम पड़ोसी देशों तथा इस क्षेत्र के देशों से शांतिपूर्ण रिश्ते रखना चाहते हैं. हम तो भारत से दोस्ती चाहते हैं लेकिन वह अफगान अवाम की मदद करने की जगह हमलावर का पक्ष लेकर गलती किए जा रहा है.

• क्या पूर्व राजा जहीर शाह मेलमिलाप कराने में कोई भूमिका अदा कर सकते हैं?

यह हैरानी की बात है कि भारत अवाम द्वारा नकार दिए गए एक बादशाह की वापसी चाहता है. लेकिन अब उनकी कोई भूमिका नहीं बची है. पूरा मुल्क चुनी हुई सरकार के पक्ष में है. दस साल की जंग ने अफगानियों को बदल दिया है. 'अब वे चुनी हुई सरकार से कम' कुछ भी मंजूर नहीं करेंगे.

• कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान में लड़ रहे मुजाहिदीन प्रवासी मुजाहिदीन नेताओं को सत्ता में हिस्सेदारी देना किसी भी सूरत में मंजूर नहीं करेंगे.

अफगानिस्तान में लड़ रहे सभी कमांडर अपनी पार्टियों का आदेश मानते हैं. वे पेशावर स्थित सात मुजाहिदीन गुटों के गठबंधन—इस्लामिक यूनिटी ऑफ अफगान मुजाहिदीन (आईयूएएम)—के फैसले को मानते हैं. यह प्रवासी सरकार नहीं होगी बल्कि यह सरकार अफगानिस्तान में ही बनेगी और इसमें सभी कमांडर शामिल होंगे.

• यानी आपको नहीं लगता कि अफगानिस्तान में विभिन्न गुटों के बीच सत्ता संघर्ष के कारण गृहयुद्ध भड़क सकता है.

अंतरिम सरकार की वजह से गृहयुद्ध भड़कने का कोई सवाल ही नहीं उठता.

• मैंने सुना है कि अफगानिस्तान में हुए नुकसान के लिए रूस से हर्जाना मांगने के लिए आप संयुक्त राष्ट्र संघ या दूसरे अंतरराष्ट्रीय संगठनों से अपील करने की योजना बना रहे हैं.

हां, लेकिन आजादी मिलने के बाद ही. हालांकि हर्जाने की रकम अभी तय नहीं हो पाई है. 13 लाख लोगों के जीवन की कीमत आंकना संभव नहीं है.

यहां मैं एक बात और कहना चाहता हूं. राजीव गांधी ने कहा है कि मुजाहिदीनों की सरकार भारत के लिए ही नहीं, पाकिस्तान के लिए भी खतरा साबित होगी. मैं कहना चाहता हूं कि मुजाहिदीनों की सरकार किसी के लिए खतरा नहीं बनेगी.

• कुछ लोगों की चिंता यह है कि अफगानिस्तान में जम्हूरियत नहीं बल्कि कट्टरपंथी सरकार बहाल होगी.

कट्टरपंथी से आपका मतलब क्या है? हम मुसलमान हैं. जाहिर है कि यह एक इस्लामी देश है और वहां इस्लामी सरकार होगी.

• अफगानिस्तान में अल्पसंख्यकों—हिंदू, सिख, सिंधी—की संख्या भी अच्छी-खासी है. इस्लामी अफगानिस्तान में उनका भविष्य क्या होगा?

उन्हें सभी मानवाधिकार प्राप्त होंगे. वे अफगानिस्तान में वर्षों से रह रहे हैं. और आगे भी वे वैसे ही रहते रहेंगे.

• हाल ही में जलालाबाद में मुजाहिदीनों ने सिखों की बड़े पैमाने पर हत्या की.

यह कम्युनिस्टों ने और सरकार ने की थी. तमाम अखबारों में छपा कि कम्युनिस्ट पार्टी के दो कार्यकर्ता वहां गए और मारकाट की.

• यानी चुनाव लड़ रहे सिखों का विरोध पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान कर रही थी, मुजाहिदीन नहीं.

नहीं. सिखों ने मुजाहिदीनों का साथ दिया है. उन्होंने जंग में हिस्सा लिया, हमें हथियार दिए. वे हमारे समाज के अहम हिस्सा रहेंगे.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पाकिस्तान

फिर अनिश्चितता का दौर

वजीरे आज़म की बरखास्तगी से लोकतांत्रिक उम्मीदों को धक्का

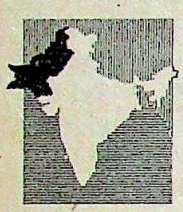

जिया-उल-हक कब क्या कर बैठें कोई नहीं जानता, न उनके दोस्त और न दुश्मन. वजीरे आज़म मोहम्मद खां जुनेजो को बरखास्त करने के कुछ हफ्ते पहले से ही इस्लामाबाद में एक चुटकुला खूब चल रहा था. इसके अनुसार जिया अपने बाग में एक पेड़ के नीचे बैठकर चाय पी रहे थे और ऊपर बैठे दो कौवे उन्हें देख रहे थे. एक कौवा उड़ा और जिया के प्लेट से एक बिस्कुट झपट ले गया. पेड़ पर बैठे कौवे ने अपने साथी से कहा, "ऐसा फिर मत करना, यह जिया है." लेकिन अपनी सफलता पर खुश पहले कौवे ने फिर झपट्टा मारकर दूसरा बिस्कुट भी उठा लिया. नाराज जिया ने घर की ओर जाते हुए धमकी दी कि अभी बंदूक लाकर मजा चखाता हूं. और लालची कौवे ने जब तीसरा झपट्टा मारा तो जिया ने दन से अपनी पिस्तौल निकाली और उसे वहीं ढेर कर दिया. जिंदा बचे कौवे ने कहा, "तुम्हें कहा था बच के रहना. यह कहता कुछ है, करता कुछ है."

और चुटकुले की यह पंक्ति सिंध में फिलहाल अपने छोटे से गृहनगर में शक्तिहीन होकर बैठे जुनेजो के साथ हुई घटनाओं पर भी लागू होती है. जिया ने उन्हें उस समय हटाया जब वे एक सरकारी दौरे पर फिलीपींस गए थे. इसके साथ ही उन्होंने काबीना और कौमी असेंबली भी भंग कर दी. एक ही दिन बाद चारों सूबाई असेंबलियां भंग करके वहां के वजीरे आला भी बरखास्त कर दिए गए. दो झटकों में ही जिया ने तीन साल पहले खुद बनाए अर्द्ध-संसदीय ढांचे को खत्म करके पाकिस्तान को फिर तानाशाही के अनिश्चित दौर में झोंक दिया. हालांकि उन्होंने 90 दिन के अंदर चुनाव कराने का एलान किया है पर उनकी बातों पर लोगों को बहुत भरोसा नहीं. इस बीच जिया ने 18 सदस्यीय कामचलाऊ मंत्रिमंडल का गठन कर दिया है. इस मंत्रिमंडल को जिया ने 9 जून को शपथ दिलाई. इसमें किसी को वजीरे आज़म नहीं बनाया गया है मगर ज्यादातर मंत्री जुनेजो मंत्रिमंडल के सदस्य रह चुके हैं. मंत्रिमंडल का नेतृत्व खुद जिया करेंगे.

जिया का यह दूसरा तख्तापलट संवैधानिक और इसलिए अहिंसक भी है. पहले तख्तापलट में सिंध से ही आए वजीरे आज़म जुल्फिकार अली भुट्टो को अपनी जान गंवानी पड़ी थी. 1985 में जिया ने 1973 वाला संविधान लागू किया जिसके तहत सदर को वजीरे आज़म, वजीरे आला, कौमी असेंबली और सूबाई असेंबलियां मुकर्रर करने या बरखास्त करने का अधिकार है. उन्होंने यही किया और विपक्षी दलों या आम लोगों ने इसका कोई विरोध नहीं किया. उलटे मुख्य विपक्षी दल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और नौ दलों के लोकतंत्र बहाली आंदोलन ने नए चुनावों की संभावना का स्वागत ही किया है. इन्हीं दलों ने 1985 के गैर-पार्टी चुनावों का बहिष्कार किया था. लाहौर के संविधान विशेषज्ञ एतजाज अहसान का कहना है, "अगर आईन (संविधान) के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई तो चुनाव फौरन कराने ही पड़ेंगे. नए चुनावों की तारीख और कामचलाऊ सरकार का एलान किए बिना कौमी असेंबली को तोड़ने का सदर का हुक्म कोई माने नहीं रखते इसलिए चुनावों को 29 अगस्त से आगे टाला नहीं जा सकता."

प्रणांत पंजियार

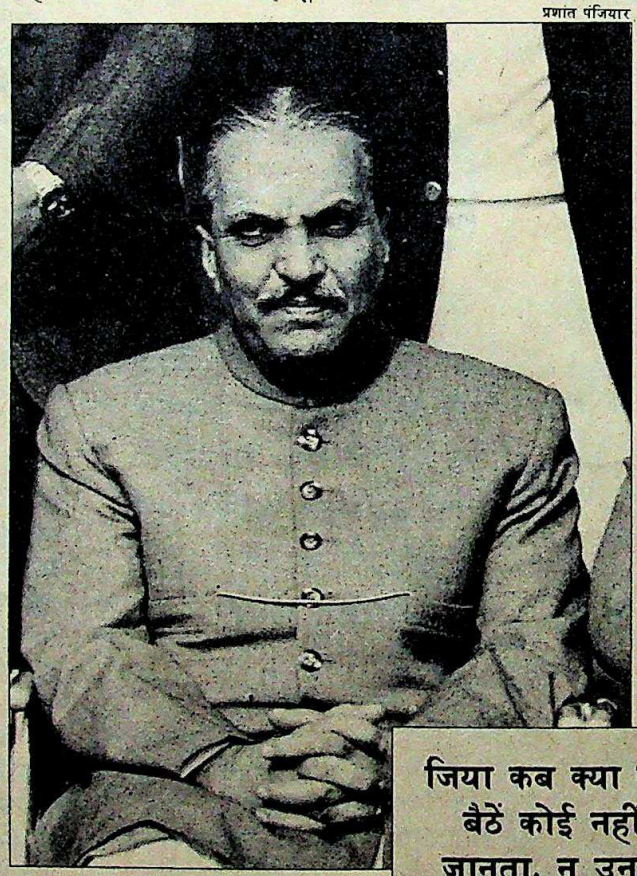

जिया कब क्या कर बैठें कोई नहीं जानता, न उनके दोस्त, न दुश्मन. उन्हें इसी में मजा आता है कि लोग उनके बारे में अनुमान लगाते रहें. इस बार वे उस समय हरकत में आए जब जुनेजो फिलीपींस में थे

लेकिन जिया के वायदे से मुकरने के संकेत अभी से मिलने लगे हैं. कामचलाऊ सरकार बनाने की उनकी कोशिश में देरी हो रही है और चुनाव पर भी वे अब उतना जोर नहीं दे रहे. अपने राष्ट्रीय प्रसारण में उन्होंने कहा कि जुनेजो के जमाने में इस्लामीकरण की मुहिम पिछड़ गई थी. इसे बढ़ावा देना उनका पहला काम होगा. फिर भ्रष्टाचार को खत्म करना और जिम्मेदारी की जज्बा बहाल करना है. उन्होंने इस्लामीकरण पर मजहबी रहनुमाओं से बातचीत की और आम आदमी को सस्ता और जल्दी इंसाफ दिलाने के लिए इस्लामी अदालतें कायम कीं.

पर जुनेजो के हिमायतियों को जिया के आरोप मंजूर नहीं हैं. उनका सवाल है कि जिया आठ साल की फौजी हुकूमत में जो नहीं कर पाए उसे जुनेजो की सिविल सरकार तीन साल में कैसे कर सकती थी. लेकिन इन लोगों की परेशानी को और बढ़ाते हुए जिया मुस्लिम लीग को बांटने में कामयाब रहे हैं. उन्होंने लीग के नवाब शरीफ को सूबा पंजाब का कामचलाऊ मुख्यमंत्री मुकर्रर किया है और इस तरह सबसे बड़े सूबे में ही वे पार्टी को तोड़ डालने

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कामयाब हो गए हैं.

जिया ने जिन संभावित कारणों से जुनेजो तत्काल हटाया है, उन पर पाकिस्तान में आम सहमति है. पहला कारण तो जिया-नेजो के बीच सत्ता का बंटवारा था और यह ता कड़वा हो चुका था. जिया के हिसाब नागरिक-सैनिक सत्ता संतुलन चल नहीं या. अपनी मुख्य कार्यकारी हैसियत जताते जुनेजो ने भस्मासुर जैसा बनने की धमकी थी पर जिया ने इस संभावना को खत्म र दिया. जहां तक लोगों को संरक्षण देने, युक्ति, तबादले और प्रोन्नति देने के धिकार की बात है, जिया को लगा कि यह जो के हाथ में चला गया है. जिया इतने से तक अव्वल हैसियत में रहे कि उन्हें न दर्जे में रहना अब कबूल नहीं था.

दूसरे, जुनेजो जिया के पसंदीदा जनरलों अहम ओहदों से हटाना शुरू करके अपनी लांघने लगे थे. जुनेजो ने दबाजी की और उन्हें इसकी मत चुकानी पड़ी. उन्होंने ले. रल मुजीबुर्रहमान को सूचना र प्रसारण मंत्रालय से हटाया. ही उन्होंने गुप्तचर विभाग के ख के पद पर जिया द्वारा तैनात स को भी हटा दिया. यह खबर थी कि जुनेजो अंतर-सेवा चर विभाग के प्रमुख को लपिंडी के नजदीक ओझरी क भंडार में हुए विस्फोट का ी बताकर हटाने की योजना रहे थे. इस विस्फोट में सैकड़ों मारे गए थे. यही विभाग गान मुजाहिदीनों को भी यार पहुंचा रहा था लिए जिया और रिका इसके साथ किसी ह की 'छेड़छाड़' पसंद कर सकते थे. जिया ने जो द्वारा कोई कदम ने से पहले ही वार दिया और फिर अमे-ा ने भी इसके खिलाफ नहीं कहा.

तीसरे, अफगान सम-ी को लेकर जिया और गो में तीखे मतभेद रने लगे थे. पाकिस्तानी कारियों के मुताबिक रिकी विदेश विभाग के लोगों की तरह जिया मानते हैं कि सोवियत कों को इतनी आसानी से नहीं चले जाने देना चाहिए और जेनेवा समझौते के बावजूद मुजाहिदीनों को मदद जारी रखनी चाहिए जिससे वे आठ महीने और रहने वाले सोवियत सैनिकों को परेशान करना जारी रखें. एक कूटनैतिक प्रेक्षक के अनुसार, "यह खतरनाक खेल है और इससे मुश्किल हो सकती है लेकिन जिया और गुप्तचर सेवा के लोग रूसियों को बाहर निकालने में मिली सफलता से बौरा गए है." दूसरी ओर जुनेजो सोवियत संघ के प्रति नरम रुख अपनाने और धीरे-धीरे उससे दुश्मनी दूर करने के पक्ष में थे. बरखास्तगी के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में जुनेजो ने अफगान मसले पर समझौते से पहले की बातचीत में उभरे मतभेदों की ओर संकेत किया भी था. मॉस्को से बातचीत की

रावलपिंडी में जुनेजो के साथ बेनजीर

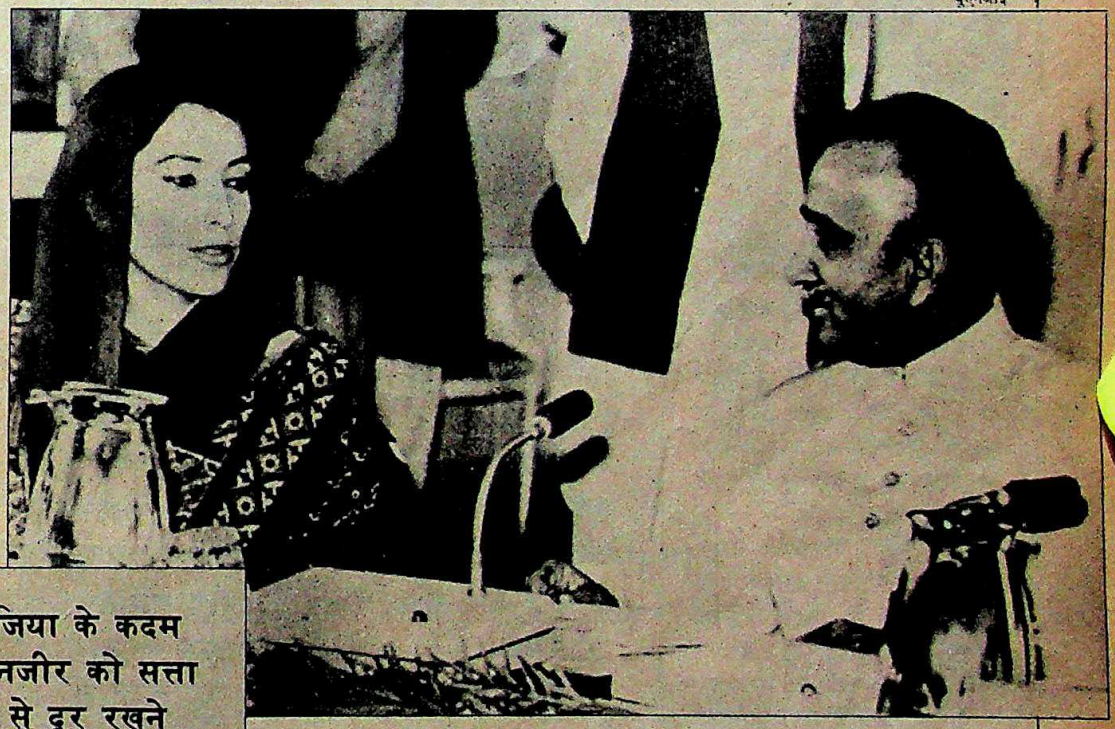

यूएनआई

जिया के कदम बेनजीर को सत्ता से दूर रखने के बजाय उन्हें अहमियत दिलाने वाले ही साबित हुए हैं. और उधर जुनेजो को उनकी बढ़ती ताकत के डर से उनका जन्मदाता ही निगल गया

शुरुआत का दावा करते हुए, जिसके बाद जेनेवा समझौता हो पाया, जुनेजो ने सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव की तारीफ की कि उन्होंने मेरी पहल का जवाब दिया. व्यंग्य के लहजे में जुनेजो ने आगे कहा, "लेकिन अपने यहां यह मामला इतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ा."

लेकिन जिया को सबसे अधिक परेशानी अपने हाथ से सत्ता धीरे-धीरे सरकते जाने से हुई. दैनिक 'मुस्लिम' के जिया समर्थक माने जाने वाले पूर्व संपादक मुशाहिद हुसैन कहते हैं, "हुकूमत से जनरल जिया का रिश्ता वैसा ही है जैसा कैथोलिक ईसाइयों में शादी का बंधन होता है जिसमें कभी तलाक नहीं होता. हकूमत से खुद-ब-खुद हट जाने का रिवाज पाकिस्तान में है ही नहीं. जिया ने जितने अरसे तक मुमकिन हो हुकूमत पर कब्जा जमाए रखने और उसे भुट्टो खानदान के किसी शख्स के हाथ न जाने देने के लिए यह फैसला किया है. यही उनका मकसद रहा है."

बेनजीर भुट्टो की पीपुल्स पार्टी के प्रवक्ता 43 वर्षीय सलमान तासीर की राय थोड़ी और तल्ख थी, "जिया का एक ही मकसद है और वह है हुकूमत में बने रहना. इसके लिए वे कुछ भी कर सकते हैं. उन्होंने अपनी फर्जी रायशुमारी के लिए तो इस्लाम का भी इस्तेमाल कर लिया." पर विडंबना यह है कि जिया का यह कदम बेनजीर को सत्ता से दूर रखने की जगह उनको ज्यादा अहमियत दिला देने वाला साबित हुआ है. नेतृत्व को लेकर हुए विवाद, अपनी शादी और गर्भवती होने की खबर के कारण पीपुल्स पार्टी की इस आकर्षक और करिश्माई नेता को भी मुश्किल हो गई थी. लेकिन अब उनका राजनैतिक सितारा फिर चमक उठा है. उनके गर्भवती होने का मामला अब भी रहस्यमय बना हुआ है. तासीर का कहना है कि उनकी नेता को बच्चा नहीं होने वाला है. खुद बेनजीर भी इस सवाल का जवाब देने से बचती रही हैं.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अगर वे सचमुच मां बनने वाली हैं तो जिया निश्चित रूप से चुनाव कराने में देरी करेंगे जिससे बेनजीर कारगर तरीके से चुनाव अभियान का संचालन नहीं कर सकें. इस हिसाब से पाकिस्तान के चुनाव एक मायने में अजीब कहलाएंगे क्योंकि शायद पहली बार उन पर 'जच्चा-बच्चा समस्या' का प्रभाव रहेगा.

इस बीच बेनजीर ने अपनी पहले की लाइन बदल ली है. वे अब जिया द्वारा कराए जाने वाले चुनावों में पीपुल्स पार्टी के उतरने के खिलाफ नहीं हैं. वे कहती हैं, "चुनाव एक मौका है. जिया की

सभी फोटो: रमिंदर सिंह

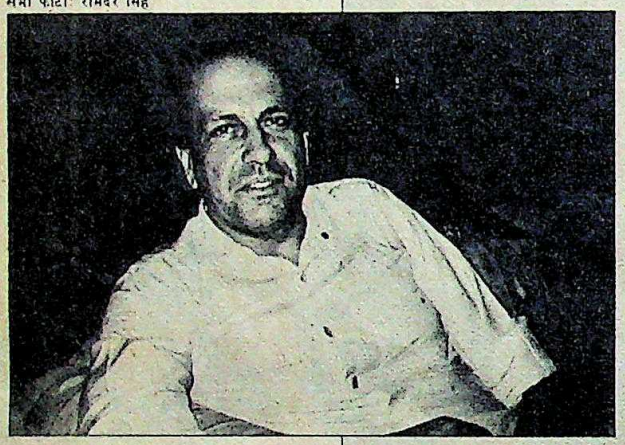

ओर से कराए जा रहे चुनावों में हिस्सा लें. उसका बायकाट करके मैदान सरकारी उम्मीदवारों के लिए छोड़ देने के चक्कर में पड़ने की जगह लोग चाहते हैं कि मुखालिफ पार्टियां इसका फायदा उठाएं."

पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सलमान तासीर कहते हैं कि जिया का मकसद सत्ता में बने रहना है. वे इस्लाम तक का इस्तेमाल कर सकते हैं

बहरहाल निराश जम्हूरियत पसंद भी इस बात से खुश हैं कि जिया ने दुबारा सैनिक शासन नहीं लादा है. लेकिन इसी कारण जुनेजो की सरकार को भी अर्द्धसैनिक सरकार कहा जाता था. तासीर कहते हैं, "परदे के पीछे सेना थी. अब वह परदा भी उतार दिया गया है." लेकिन सारे विपक्षी भी इस राय से सहमत नहीं हैं. कौमी असेंबली के पूर्व अध्यक्ष और बाद में सदन में विपक्ष के नेता रहे 45 वर्षीय फख्र इमाम का मानना है कि जुनेजो हुकूमत तो सैनिक शासन और दल वाली राजनैतिक व्यवस्था के बीच एक पुल की तरह थी. 1985 में गैर-पार्टी चुनाव कराना सबसे बढ़िया तो नहीं पर दूसरा बढ़िया विकल्प था और यह सैनिक शासन से बेहतर था. इमाम कहते हैं, "असली इम्तहान तो अगले चुनाव में होगा. अगर सरकार हारती है तो क्या वह सत्ता सौंप देगी? पाकिस्तानी सियासत की सबसे बड़ी कमजोरी यही रही कि यहां कभी शांतिपूर्वक तब्दीली नहीं हुई है."

जिया इस साल के शुरू से अपनी मंशा का संकेत देते आ रहे थे और इन्हें जुनेजो से अधिक दूरदर्शी आदमी ही पहचान सकता था. संविधान के अनुसार जिया सिविलियन सदर थे लेकिन इस साल के शुरू में उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि सेनाध्यक्ष का उनका कार्यकाल आगे भी बढ़ाया जाए.

राष्ट्रीय परिषद के पूर्व अध्यक्ष फख्र इमाम का कहना है कि जुनेजो सरकार सैनिक शासन और दलीय सरकार के बीच पुल की तरह थी

सेनाध्यक्ष का पद छोड़ने की मांग के जवाब में इस साल 7 मार्च के 'गल्फ न्यूज' को दी गई भेंटवार्ता में जिया ने अपनी मंशा जाहिर कर दी थी. उन्होंने कहा था, "मैंने जो काम हाथ में लिया है, उसे पूरा किए बगैर मैं मैदान से हटने वाला नहीं. मैं सिर्फ इसी वजह से ओहदा नहीं छोड़ने वाला कि किसी और को यह पसंद नहीं है."

इससे भी स्पष्ट संकेत उन्होंने महीने भर बाद संसद के दोनों सदनों में अपने भाषण में दिया. जुनेजो सरकार ने उनके लिए जो भाषण तैयार किया था उसे ठुकराते हुए जिया ने साफ कह दिया था कि वे ब्रिटेन की महारानी की तरह सिर्फ प्रतीक रूप में देश के प्रमुख नहीं हैं जो तैयार भाषण पढ़ें. संवैधानिक प्रमुख होने के साथ उन्हें इस व्यवस्था की रक्षा की जिम्मेदारियां भी निभानी हैं. और इस भूमिका की हैसियत से उन्होंने जुनेजो सरकार और संसद सदस्यों पर 'रिश्वतखोरी, सूबापरस्ती और इलाकापरस्ती' का आरोप लगाया. जब इस पर धन्यवाद प्रस्ताव के लिए बहस हुई तो वजीरे आजम जुनेजो ने राष्ट्रपति के भाषण पर कोई टिप्पणी नहीं की. बाद में जुनेजो ने 'इंडिया टुडे' से कहा कि उन्होंने इस मसले पर कार्रवाई के लिए अपनी पार्टी के लोगों की एक कमेटी बनाई है.

फख्र इमाम कहते हैं, "मुझे लगता है कि वे यहां क्लासिकल किस्म का पार्लियामेंटरी सिस्टम नहीं मानते. वे इसे द गॉल के पांचवें फ्रेंच रिपब्लिक की तरह मानते हैं जिसमें सदर एक पार्टी का हो तो वजीरे आज़म दूसरी पार्टी का. वजीरे आज़म और उनके वजीरों के पास गैर-मुल्की मामलों और डिफेंस के अलावा दूसरे सभी महकमे होते हैं जबकि ये दोनों महकमे सीधे सदर के हाथ में होते हैं."

इमाम का मानना सही है या गलत और फिर जिया जल्दी ही खुद को सदर बनाए रखते हुए सदारती सिस्टम ही लागू करेंगे या नहीं, इस बारे में टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी फैसले वह शख्स ले रहा है जिसके बारे में पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता. जिया बातें तो कई कर रहे हैं पर हो सकता है इसके ठीक उलट काम करें. आखिर कौवे ने भी तो यही कहा था.

—रमिंदर सिंह और इस्लामाबाद से असलम शेख

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पंचतन्त्र

पढ़ने की मौज रंगन की मस्ती

Near the river
That curves and bends,
Lived these four
Remarkable friends.

The deer, one day,
Fell in a hunter's trap.
She was found missing
When they woke from their nap.

मोड़दार बलखाती
इक नदी के पास,
रहते थे चारों
ये अनूठे यार।

एक दिन हिरनी
फंसी जाल में शिकारी के,
पता कहीं न पाया उसका
नींद से जब जागे वे।

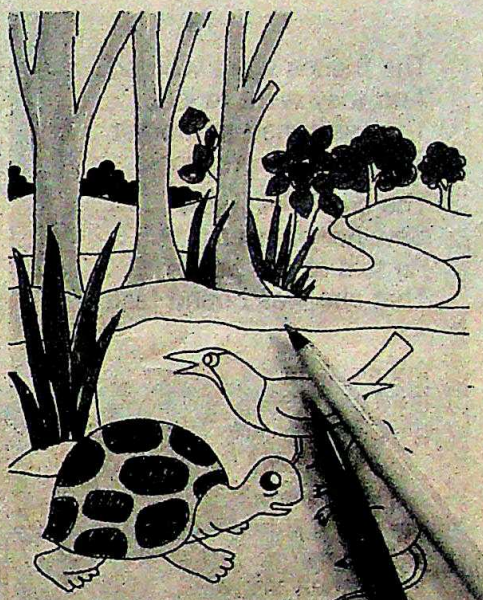

बच्चों, तुम्हारें मनोरंजन के लिए आधुनिक चित्रों से सुसज्जित कुछ पुरानी रोचक भारतीय कहानियाँ. यह कहानियाँ हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में लिखीं हैं. ताकि तुम दोनों भाषाओं का आनन्द उठा सको. रेखाचित्र विशेष रुप से बनाये गये हैं जिसमें तुम स्वयं मनपसंद रंग भर कर एक रंगीन पुस्तक तैयार कर सकते हो.

इस श्रंखला की चारों पुस्तकें वी.पी.पी. से केवल रु. 20/- में लेने के लिए अपने नाम व पते के साथ निम्नलिखित पते पर लिखिए : लिविंग मीडिया प्रा. लि., डायरेक्ट मेल युनिट, थौमसन प्रेस बिल्डिंग, देहली-मथुरा रोड़, फरीदाबाद- 121 007 (हरियाणा).

यह पुस्तकों की श्रंखला लिविंग मीडिया इंडिया प्रा. लि. के नाम चैक, मनी आर्डर या डिमान्ड ड्राफ्ट भेजने पर भी मिल सकती है.

अभी कोई पैसे भेजने की ज़रुरत नहीं है !

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

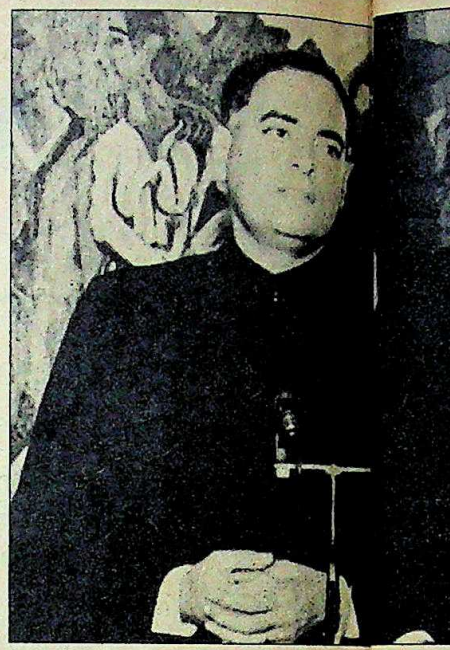

प्रधानमंत्री का विदेश दौरा

सद्भावना की पूंजी के लिए

भारत में पूंजी निवेश के लिए सीरिया व प. जर्मनी को राजी करना

लगता है प्रधानमंत्री राजीव गांधी पक्के सेल्समैन बनते जा रहे हैं. उनका यह रूप पिछले महीने टोक्यो की उनकी यात्रा के दौरान सामने आया. और अब पश्चिम जर्मनी के दौरे में यह छवि और भी उभरी. वहां उन्होंने चांसलर हेल्मुट कोल और प. जर्मनी के उद्योग जगत के सितारों को भारत में पूंजी निवेश बढ़ाने को राजी करने के लिए सारी तिकड़म भिड़ा दी.

उन्हें यह भूमिका अपने लिए उपयुक्त लगती है शायद. प. जर्मनी के उद्योगपतियों के कठिन सवालों का उन्होंने बड़ी अच्छी तरह जवाब दिया. मसलन इन उद्योगपतियों ने मीन-मेख निकालने के लिए बदनाम भारतीय नौकरशाही पर कई शंकाएं प्रकट की. और फिर इस बात का भी हवाला दिया कि भारत तो पहले ही जापानी व्यवसायियों से उनके लिए 'तेजी से काम निबटाने वाली व्यवस्था' तैयार करने का वायदा कर चुका है. राजीव ने साफ कर दिया कि जर्मन व्यवसायियों के लिए 'कुछ विशेष क्षेत्रों में' भारत अपने दरवाजे खोलने को तैयार है.

लेकिन उन्हें यह भी एहसास हो रहा है कि आला दर्जे का सेल्समैन बनकर ऐसे वायदे करने पड़ सकते हैं जिन्हें पूरा कर पाना मुश्किल हो सकता है क्योंकि आखिरकार काम तो नौकरशाही को ही करना है. कोल और जर्मन उद्योगपतियों दोनों ने ही साफ जता दिया कि उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी जापान को 'विशेष सहूलियतें' देने की भारतीय पेशकश से वे नाखुश हैं. राजीव उनकी आहत भावनाओं को सहलाने के लिए विशेष प्रयत्नशील दिखे. उन्होंने यह वायदा तो किया कि आपसी सहयोग के प्रस्ताव को वे अविलंब मंजूरी दिलवाएंगे, लेकिन उनके लिए 'तेजी से काम निबटाने वाली व्यवस्था' बनाने का वायदा नहीं किया.

लेकिन इसके बावजूद राजीव अपनी बात उन्हें समझाने में सफल रहे. यह मात्र संयोग नहीं था कि एसोसियेटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री (एसोचैम) के बैनर तले कुछ बड़े भारतीय उद्योगपति राजीव के जर्मनी पहुंचने के एक सप्ताह पहले से ही जर्मन उद्योगपतियों से बातचीत चला रहे थे.

ऐसा नहीं है कि जर्मन व्यवसायियों को कायल करने के लिए इतनी उच्चस्तरीय पहल की जरूरत थी. 'एसोचैम' प्रतिनिधिमंडल के अगुआ ललित थापर कहते हैं, "भारत में पूंजी निवेश के लिए जर्मन व्यवसायी कुछ ज्यादा ही इच्छुक हैं. इसकी मुख्य वजह है जापानियों का यहां प्रवेश."

इस लिहाज से राजीव ने अच्छे सेल्समैन की ही मिसाल पेश की. जर्मन लोग जापानियों की बात आने पर बड़े ईर्ष्यालु और संवेदनशील हो उठते हैं. जापान जहां भी कदम रखेगा वे जरूर वहां जाएंगे. राजीव के एक प्रमुख आर्थिक सलाहकार ने कहा, "जर्मन व्यवसायियों को यह एहसास हो गया है कि भारत में छोटी कार के बाजार की वे काफी समय से अनदेखी करते आए हैं. और अब नई दिल्ली से मिली हरी झंडी के बाद वे भारतीय बाजार पर अपनी पकड़ जमाने के लिए तत्पर दिखते हैं."

दरअसल, राजीव की बॉन यात्रा के दौरान ही यह संकेत दे दिया गया कि भारत अब पूंजी निवेश और लाइसेंस के मामले में उदारता बरतने को तैयार हैं. राजीव यह वायदा 1984 से ही करते आए हैं. लगता है कि भारत सरकार ने तैयारी अच्छी की थी. 1990 तक जर्मनी और जापान ही ऐसे दो देश होंगे जिनके पास पूंजी का भंडार होगा. और इन दोनों को फुसला कर भारत ने यह पक्का करने की कोशिश की है कि इन देशों की पूंजी का बड़ा हिस्सा भारत में ही लगे. वैसे, जर्मनी का आर्थिक महत्व भी अधिक है. यूरोपीय आर्थिक समुदाय में एकजुटता 1992 तक बहाल हो जाने की उम्मीद है. और इस ताकतवर संगठन में पश्चिम जर्मनी एक बड़ी ताकत होगा.

इसके अलावा राजनैतिक बातचीत का भी उतना ही महत्व है. देश में तमाम समस्याओं से घिरे होने के बावजूद राजीव की हैसियत अब एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के नेता की हो गई है. सीरिया के राष्ट्रपति असद से लंबी बातचीत हो या कोल से उतनी ही व्यापक वार्ता, राजीव ने बड़े विश्वास के साथ अंतर-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सभी फोटो: पीआईबी

ग जापा-ष्ट्रीय मसलों पर अपनी पकड़ जाहिर की.
र्यालु और सद और कोल दोनों ही अपने दबंग व्यक्ति-
जहां भी के बूते अपने अपने देश में खासा दबदबा
राजीव के ते हैं. लेकिन दमिश्क और बॉन दोनों ही
ने कहा, हों पर राजीव ने अपने व्यक्तित्व की छाप
स हो गया ड़ी. एक तो उनका अपना व्यक्तित्व आक-
ार की वे क है, दूसरे उन्हें एक बड़े घराने के होने का
ू हैं. और री लाभ मिलता है. राजीव बारीकी से इस
के बाद वे भ को भुनाने में लगे हैं.
जमाने के सीरिया और पश्चिम जर्मनी में बातचीत

दौरान यह साफ हो गया कि
यात्रा के रत में दूसरे देशों की दिलचस्पी
कि भारत की राजनैतिक व औद्योगिक
मामले में सियत के कारण जगी है. एशिया
जीव यह भारत का मुख्य प्रतिद्वंद्वी चीन
लगता है श्चिमी देशों को यह विश्वास
की थी. हीं दिला पाया कि वह अपने
ऐसे दो वाजे उनके लिए खोलने को
ार होगा. ार है. ईरान और सऊदी अरब
त ने यह से देशों को अपनी 'सिल्कवर्म'
इन देशों साइल बेचकर उसने इन देशों
ही लगे. और भड़काया ही. यही
धिक है. रण है कि राजीव भारत की
एकजुटता जनैतिक और आर्थिक स्थिरता
म्मीद है. ले पहलू पर जोर देते रहे और
म जर्मनी में कामयाब भी रहे.

त का भी उच्च तकनीक के प्रति मुग्ध
मस्याओं क्ति की राजीव की छवि का
हैसियत जर्मनी और जापान जैसे देशों
ी हो गई असर पड़ता है. स्टटगार्ट और

से लंबी
व्यापक
थ अंतर-

■ सीरिया के प्राचीन शहर
मीर में राजीव और सोनिया:
लिया के नेताओं पर नई छाप

■ राजीव राष्ट्रपति असद (एकदम बाएं) और चांसलर कोल के साथः लुभाने की कला

म्युनिख के अत्याधुनिक कारखानों और शोध केंद्रों के दौरों के दौरान उच्च तकनीक की अपनी समझ का उन्होंने जो परिचय दिया उसका भी खासा असर पड़ा.

इस तरह राजीव के हाल के दौरे उपलब्धियों और विसंगतियों की मिसाल पेश करते हैं. दमिश्क का दौरा खालिस राजनैतिक था, तो बॉन यात्रा मुख्य तौर पर आर्थिक उद्देश्यों के लिए. दोनों ही मामलों में नई दिल्ली ने एक निश्चित नीति का परिचय दिया. सामरिक शक्ति और असद के असरदार व्यक्तित्व के कारण सीरिया अरब राजनीति में एक बड़ी ताकत है. भारत चाहता था कि सीरिया उसकी अफगानिस्तान नीति—नजीबुल्ला सरकार बनी रहे—का समर्थन करे. और यह भी कि अरब खेमे में उसका कोई दोस्त बने जो इस्लामी सम्मेलन जैसे मंचों पर पाकिस्तान के भारत विरोधी अभियान का जवाब दे सके.

लेकिन कूटनीतिक खामियां भी इन दौरों के दौरान नजर आईं. सीरिया और बॉन दोनों जगहों पर तब भारतीय राजदूत नहीं तैनात थे जब राजीव वहां के दौरे पर थे. दमिश्क में कुछ महीनों से कोई राजदूत नहीं है. और इसकी एकमात्र वजह यही है कि विदेश मंत्रालय वहा अपना कोई प्रतिनिधि भेजने की ताकत नहीं जुटा पाया है. विदेश सेवा के अधिकांश अधिकारी दमिश्क जाने को तैयार नहीं हैं. बॉन में खाली स्थान की पूर्ति नहीं हो पाई है. और राजीव के आगमन के मात्र एक सप्ताह पहले अफरातफरी में टोक्यो में भारतीय राजदूत महादेवन को बॉन भेजा.

लेकिन इन दौरों से एक बात स्पष्ट हो गई है कि राष्ट्रपति रेगन के बाद राजीव को ही सबसे ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है. सीरिया में सेना के दबदबे की वजह से सुरक्षा इंतजाम ज्यादा दिखे नहीं. लेकिन बॉन और प. जर्मनी के अन्य शहरों में राजीव की सुरक्षा के लिए बेहद कड़ा इंतजाम किया गया था. केवल रेगन की सुरक्षा व्यवस्था ही 'नंबर वन' स्तर की होती है. इससे होने वाली परेशानियों के आदी नहीं रहे जर्मन कार चालकों की परेशानी साफ झलक रही थी. राजीव के लिए पूरा-का-पूरा रास्ता जाम कर दिया जाता था और हर कदम पर बंदूकधारी जवान तैनात रहते थे. ज्यादातर मौकों पर राजीव इलाइट फेडरल बोर्डर गार्ड्स के हेलीकॉप्टरों से अपने गंतव्य पर गए. ये हेलीकॉप्टर तब भी आसमान की चौकसी कर रहे होते जब कभी राजीव का बोइंग 747 विमान उतरता अथवा उड़ान भरने को होता.

सोनिया गांधी अपने पति के साथ न्यूयॉर्क नहीं गईं तो इसे लेकर भी तरह-तरह की अटकलें लगाई गईं. उनका कार्यक्रम जाहिर हो गया तो राजीव के सहायक मुश्किल में पड़ गए. लेकिन जब राज खुल ही गया तो उनकी यह दलील बचकानी ही लगी कि 16 घंटे की यात्रा करके न्यूयॉर्क जाना और वापस आना उनके लिए बेकार ही होता. लेकिन ये अफवाहें भी फैलीं कि वे आननफानन में इटली हो आना चाहती थीं. वैसे, सोनिया ने इस दौरे में संकोच का आवरण अपने चेहरे से उतार फेंका और कई बार वे मुस्कराती हुई दिखीं.

देश के सबसे बड़े सेल्समैन बनने की राजीव गांधी की इन कोशिशों को इससे बल ही मिलेगा. अपने सहयोगियों से बेहतर तालमेल की वजह से उन्हें काफी फायदा हुआ है और अब उन्हें घरेलू चिंताओं से परेशान नहीं होना पड़ता. लगता है राजीव के पुराने शानदार, 1984 वाले दिन लौट रहे हैं.

—दिलीप बॉब, दमिश्क और बॉन में.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारत-नेपाल सीमा

तस्करी की स्वर्ण रेखा

विदेशी सामान का तेजी से फलता-फूलता कारोबार

आपको चीनी हवाई चप्पल चाहिए या कंप्यूटर के जापानी पुर्जे, या आप गीवेंची इत्र या अत्याधुनिक दूरबीन की तलाश में हैं? तो आपको दुबई या हांगकांग जाने की जरूरत नहीं. यह सारा सामान देश की सीमा पार करते ही नेपाल में मिल जाएगा. नई दिल्ली से सबसे नजदीक ऐसे स्थान पर कार से मात्र छह घंटे की यात्रा करके पहुंचा जा सकता है. और तो और, विदेशी मुद्रा का जुगाड़ करने का झमेला भी नहीं. भारतीय रुपया वहां तय दर से कुछ ऊंची कीमत पर ही चल जाता है. इतना ही नहीं सीमा-शुल्क तथा वीसा-पासपोर्ट के अधिकारियों का झंझट नहीं.

खरीदारों का यह बेहतरीन बाजार और तस्करों का स्वर्ग नेपाल की सीमा के पार टनकपुर से सोनौली तक उत्तर प्रदेश के सात जिलों में फैला हुआ है. सीमा की इस 728 किमी लंबी पट्टी पर सिर्फ आठ चौकियां हैं. भारतीय सीमा से महज चार किमी की दूरी पर तस्करों के 12 इन बड़े बाजारों तक पहुंचने के लिए करीब 15 पक्की सड़कें और कम-से-कम 500 कच्चे तथा कंकड़-पत्थर बिछे रास्ते हैं. ये बाजार सुबह सात बजे से आधी रात तक खुले रहते हैं और हर रोज इनका कारोबार करीब 1.5 करोड़ रुपए का होता है.

बहराइच जिले के पार नेपालगंज बाजार में भारतीय मूल के नेपाली नागरिक 70 वर्षीय झूठाराम खेतान की बहुत पुरानी दुकान है. वे कहते हैं, "90 फीसदी से अधिक कारोबार भारतीय मुद्रा में ही होता है." और तस्करी बाजार में सामान की कीमत भी काफी कम है. नेशनल का जी-12 मॉडल का वीसीआर सिर्फ 9,500 रुपए में मिल जाता है. भारत में कहीं भी इसकी कीमत 13,500 तक मिल जाती है. तोशिबा का टीवी 10,000 रुपए में मिल जाता है जबकि दूसरी जगहों पर इसकी कीमत 15,000 होती है. और आम तौर पर 3,500 से 5,000 रुपए प्रति किलो बिकने वाली चरस इन बाजारों में सिर्फ 700 से 1500 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल जाती है.

इन सभी 12 बाजारों तक पहुंचना बहुत आसान है. यदि कोई अपनी निजी गाड़ी उस पार नहीं ले जाना चाहता तो उसे तांगे और रिक्शे मिल जाएंगे. आम तौर पर सरकारी अधिकारी अपनी गाड़ियां सीमा पर ले जाना पसंद नहीं करते. चार बड़े बाजार हैं— लखीमपुर खीरी जिले के पार धानगढ़ी, बस्ती जिले के पार कृष्णनगर, बहराइच जिले के पार नेपालगंज और गोरखपुर जिले के पार भैरहवां. इन चारों बाजारों से नेपाल की राजधानी काठमांडू तक मोटर से 10-12 घंटे में पहुंचा जा सकता है.

बस्ती जिले के बढ़नी शहर के नजदीक कृष्णनगर थोक व खुदरा खरीदारों के लिए एक बड़ा बाजार है. बढ़नी और कृष्णनगर के बीच सिर्फ 30 मीटर का क्षेत्र पड़ता है जिस पर किसी का अधिकार नहीं. मात्र 10,000 आबादी वाले कृष्णनगर में विदेशी जिंसों की 500 दुकानें हैं. एक कपड़ा व्यापारी ने कहा, "यहां के 500 दुकानदार नेपाल सरकार को सालाना 40 लाख रुपए आयकर के बतौर देते हैं." इससे नेपाल को भारी आमदनी होती है.

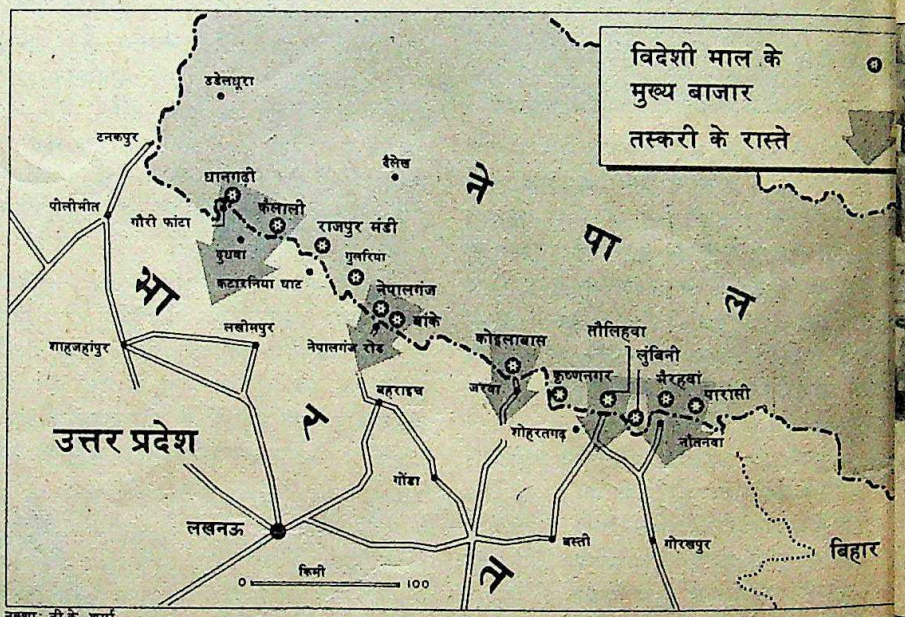

नक्शा: बी.के. शर्मा

भैरहवां बाजार में लोग विदेशी सामान खरीदते हुए: भारी व्यवसाय

सभी फोटो: आर.के. गुप्ता

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

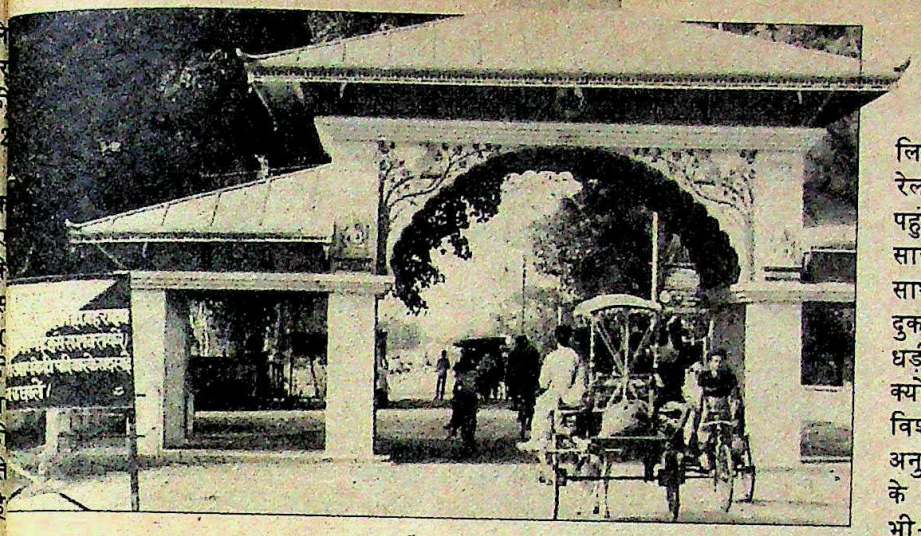

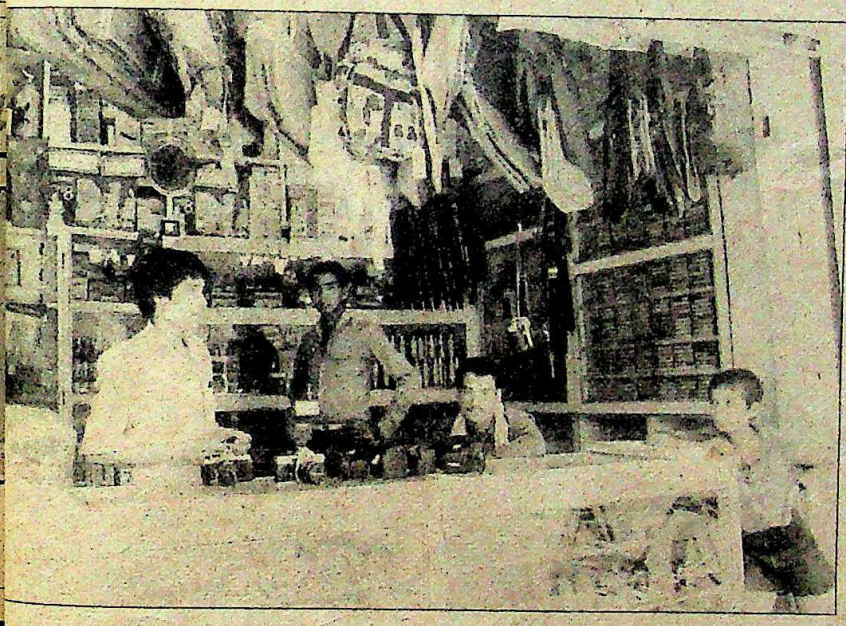

कारोबार की चुस्ती को जांचने के लिए 'इंडिया टुडे' ने हांगकांग निर्मित एक सुंदर इमरजेंसी लाइट के लिए 250 रुपए अदा किए और उसे बढ़नी रेलवे स्टेशन के पास खड़ी एक कार तक पहुंचाने को कहा. कुछ मिनटों बाद ही साइकिल से एक 14 वर्षीय लड़का पैकेट के साथ वहां पहुंच गया. सामान पहुंचाने वाले दुकानदार ने कहा, "किसी तरह की धोखा-धड़ी या मिलावट का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि इस तरह तो हम खरीदारों का विश्वास ही खो बैठेंगे." उस दुकानदार के अनुसार कृष्णनगर से आठ से दस लाख रुपए के विदेशी सामान— कई बार तो सोना भी— से लदे पांच या छह ट्रक हर रोज जाते हैं. आम तौर पर इनकी मंजिल लखनऊ, कानपुर और नई दिल्ली ही होती है.

और इसमें कहीं रोकटोक का सवाल ही नहीं है. सीमा शुल्क के सुपरिंटेंडेंट के मातहत 16 इंस्पेक्टर और 34 सिपाही हैं. पर वे दखलंदाजी का दुस्साहस नहीं मोल लेते क्योंकि यह जोखिमभरा मामला है. इसी तरह पुलिस के भेदियों के प्रति भी तस्करों का रवैया बर्बर ही है. 40 वर्षीय बड़का तस्कर है. उसने पिछले साल सितंबर में एक दूसरे तस्कर मिर्जा के एक ट्रक को पकड़वाने में पुलिस की मदद की थी. मिर्जा के आदमियों ने बड़का का अपहरण कर लिया. उसे कृष्णनगर ले गए और बुरी तरह मारने-पीटने के बाद उससे उसके ट्रैक्टर और ट्रक को बेचने के इकरारनामे पर दस्तखत करवाए.

लखीमपुर जिले से लगे धानगढ़ी जैसे बड़े बाजारों में भी इसी स्तर पर तस्करी होती है. धानगढ़ी का बाजार खासकर सरकारी अधिकारियों को अधिक पसंद है. 300 से अधिक दुकानों की सदस्यता वाले धानगढ़ी व्यापारी संघ के कोषाध्यक्ष, 50 वर्षीय जगदीश अवस्थी कहते हैं, "किसी रविवार के दिन यहां आइए. यहां आप उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों के सरकारी अधिकारियों और उनके परिवारवालों को पाएंगे." इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान की एक लोकप्रिय दुकान के मालिक, भारतीय नागरिक मदन चंद कोठारी कहते हैं, "यहां से ज्यादातर सामान या तो भारतीय बाजारों में जाते हैं या फिर भारतीय खरीदार उन्हें ले जाते हैं." लखीमपुर खीरी में सीमा शुल्क के सुपरिंटेंडेंट बी.एन. सिंह इस बात से इनकार करते हैं कि यहां कोई संगठित तस्करी होती है. लेकिन वे कहते हैं,

(ऊपर से) नेपालगंज का प्रवेश द्वार; भैरहवां में बिक्री के सामान; और नेपाल में प्रवेश करतीं महिलाएं: खुली सीमा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"यदि यहां 80 किमी में फैली सीमा पर 50 रास्ते हैं तो हम आठ इंस्पेक्टरों और 17 सिपाहियों की सहायता से इन सभी पर नजर नहीं रख सकते."

बहराइच जिले के रुपहदिया कस्बे की सीमा से लगे नेपालगंज बाजार की भी लगभग यही कहानी है. यहां सीमा पर दोनों तरफ पांच-पांच चौकियां हैं और कुछ हटकर एक-एक चौकी और है. लेकिन यहां सीमा पार करने के दूसरे करीब 80 रास्तों के कारण तस्करी कोई बहुत मुश्किल नहीं है. और कोई पकड़ा भी जाए तो जुर्माना भी काफी कम है. कानून के रखवालों की मुट्ठी से फिसलने के लिए सिर्फ पांच रुपए काफी

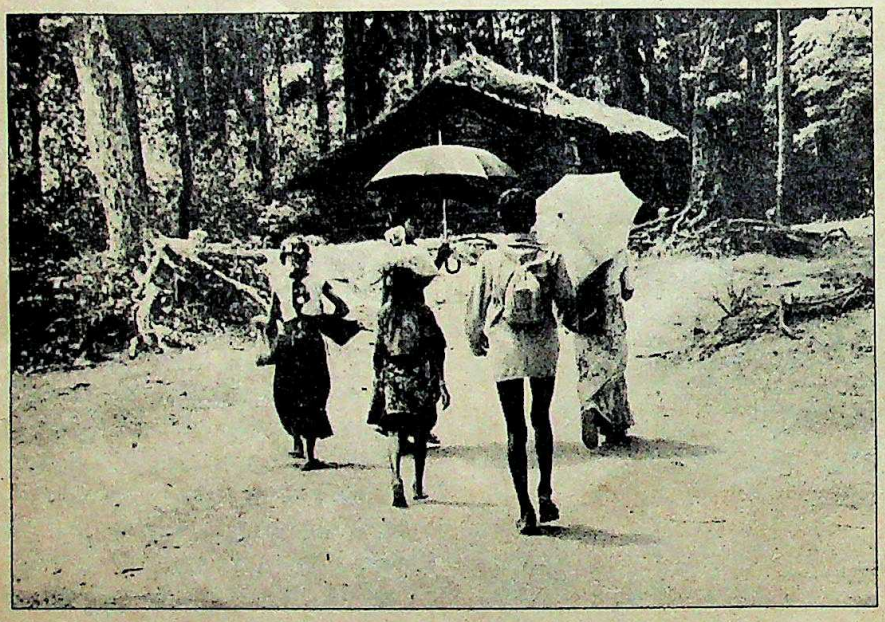

हैं. दरअसल यहां के समझदार तांगेवाले अपने सवारियों से यह रकम पहले ही ले लेते हैं और चौकियों पर खुद ही दे आते हैं. सीमा शुल्क इंस्पेक्टर बी.बी.एल. तिवारी कहते हैं, "निजी प्रयोग के लिए सामान लाने वालों को हम तंग नहीं करते. हम तो सिर्फ तस्करों की तलाश में रहते हैं."

गोरखपुर में सोनौली सीमा के पास नेपाल का भैरहवां बाजार भी खुदरा खरीदारों का आकर्षण है. विदेशी सामान की यहां भरमार है. यहां रोज का कारोबार 2 से 5 लाख रुपए का है. सीमा शुल्क सुपरिंटेंडेंट सुनील चक्रवर्ती कहते हैं, "यह मुख्य रूप से खुदरा बाजार है. यहां बड़े गिरोह नहीं हैं." लेकिन इस साल मार्च में नौतनवा में 60,000 रुपए कीमत की 12 किलो चरस और इसके पहले 7 लाख रुपए कीमत के सोने के साथ दो व्यक्तियों के पकड़े जाने से लगता है कि शायद यहां भी माहौल अब बदल रहा है.

इसका एक बड़ा कारण तो सोने की लालच है. भारत में पाए जाने वाले 50 फीसदी शुद्धता वाले सोने के मुकाबले नेपाली सोना .999 फीसदी शुद्ध होता है. और दाम में फर्क भी काफी है. भारतीय सोना 150 से 300 रुपए प्रति तोला महंगा है (भारत में सोना फिलहाल 3,280 रु. प्रति तोला है). सोने की तरह ही अब कंप्यूटर के पुर्जों की मांग भी बढ़ गई है. पिछले साल जून में नौतनवा में एक नौजवान को 10.50 लाख रुपए के कंप्यूटर पुर्जों के साथ पकड़ा गया.

हालांकि बड़े बाजारों के आसपास पकड़े

भारत में घुसते लोगः कोई रोक-टोक नहीं

गए सामान ऊंट के मुंह में जीरे के सामान ही हैं पर इनसे धंधे का अंदाज तो लगता ही है. पिछले साल सीमा शुल्क विभाग के कर्मचारियों ने 180 लाख रुपए का सामान पकड़ने का लक्ष्य कायम किया था पर पकड़ा गया 243 लाख रुपए कीमत का सामान. इस साल का लक्ष्य 325 लाख का सामान पकड़ना है और अब तक 91.5 लाख कीमत का सामान पकड़ा जा चुका है.

तस्करी से होने वाले राजस्व की क्षति से ज्यादा चिंताजनक है गैरकानूनी हथियारों की तस्करी की आशंका. रॉ और खुफिया ब्यूरो की पिछले साल की रिपोर्टों से पता चलता है कि भारत-नेपाल सीमा से एके-47 एसॉल्ट राइफलों के अलावा भारी मात्रा में चीनी हथियार भारत में तस्करी करके लाए गए. केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों ही स्थिति की गंभीरता से अवगत है. इसलिए केंद्र सरकार ने सोनौली चौकी को छोड़कर बाकी किसी चौकी से नेपालियों के अलावा सभी विदेशी नागरिकों की आवाजाही पर रोक लगा दिया है.

अपनी तरफ से उत्तर प्रदेश पुलिस सीमा पर कड़ी चौकसी बढ़ाने और सीमा पर 1 से 20 किमी दूरी तक के मौजूदा थानों को और सशक्त बनाने की योजना बना रही है. इस व्यवस्था में करीब 200 करोड़ खर्च आएगा. पुलिस के महानिदेशक आर.एन. गुप्ता इस प्रस्ताव पर इसकी 'नज़ाकत' को ध्यान में रखकर बात करने से मना कर देते हैं पर सरकारी सूत्रों ने संकेत दिया कि इस प्रस्ताव के तहत 40 नए थाने बनाने और सीमा पर 100 निगरानी बुर्ज बनाने की योजना है. सरकार 12 नए थाने बनाने के प्रस्ताव को पहले मंजूरी दे चुकी है.

राज्य सरकार ने केंद्र से सीमा पर भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल की तरह एक अर्द्धसैनिक बल को तैनात करने की मांग की है. लेकिन पिछले साल जनवरी और फिर जून में रखे गए इस प्रस्ताव को केंद्र ने इस बिना पर नामंजूर कर दिया कि ऐसी किसी पहल से नेपाल नाराज हो सकता है. उधर तस्करी के कारण नेपाल सरकार को सीमा पर के बाजारों से आयकर, बिक्रीकर, सीमा कर और चुंगी के रूप में भारी आमदनी होती है.

खुफिया ब्यूरो की 1981 के सर्वेक्षण के मुताबिक नेपाल हांगकांग, सिंगापुर, कोरिया और चीन से साल में 300 करोड़ रुपए का सामान आयात करता है. लेकिन वहां देसी बाजार में इस आयातित सामान का मात्र 10 फीसदी बमुश्किल खप पाता है, बाकी सारा भारत चला आता है. सर्वेक्षण में कहा गया है कि रोज 1.5 करोड़ से अधिक की भारतीय मुद्रा सीमा पार चली जाती है.

इस मसले से संबंधित उत्तर प्रदेश सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं, "अब तक हम नेपाल की दोस्ती के नाम पर तस्करी होने देते थे. लेकिन अब इस पर फिर से विचार करने का समय आ गया है." हमें पंजाब से सीख लेनी चाहिए. वहां भी पाकिस्तान से लगी सीमा खुली है. और फिर पंजाब का साया इस ओर की सीमा पर भी पड़ सकता है. पंजाब से लगे उत्तर प्रदेश के तराई इलाके आतंकवादियों के पनाहगाह हैं ही. टू-इन-वन की तस्करी एके-47 राइफलों की तस्करी से थोड़ी अलग जरूर है. पर जब तक अधिकारियों की नींद टूटेगी तब तक सीमा पर हथियारों की तस्करी का कारोबार अपनी रफ्तार पकड़ चुका होगा.

—दिलीप अवस्थी, भारत-नेपाल सीमा से

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ओडीसा

बीवी को बेचने की मजबूरी

गंजम जिले के मुंडापोट्ट आदिवासी भुखमरी के कगार पर

गहरा सांवला रंग, तीखे नैन-नक्श और चमकदार आंखें, मैली-कुचैली साड़ी में आधा तन ढांपे 25 वर्षीया कांता के व्यक्तित्व की प्रमुख पहचान हैं. 40 वर्षीय पंचा पात्रो पांच महीने पहले उसे ओडीसा के गंजम जिले के रंभा गांव से 60 रुपए में 'खरीदकर' लाया था. कांता अब पात्रो की चौथी पत्नी है, और जिले में असका से 10 किलोमीटर दूर खंडरपल्ली के नजदीक एक पहाड़ी के नीचे झोंपड़ी में पति के साथ रहती है. अपनी पहली पत्नियों के बारे में पात्रो बताता है, "मेरी दो पत्नियों—जम्मा और सावित्री—की मौत हो गई और तीसरी कुंतला मेरी गरीबी के कारण मुझे छोड़कर भाग गई. तब मैं कांता को खरीदकर लाया."

उनके पास ही पात्रो की 16 वर्षीया बेटी लक्ष्मी और उसका 20 वर्षीय पति सान्या खड़ा है. सान्या भी अपनी पहली पत्नी गोलंदरी को आंध्र प्रदेश से 100 रुपए में खरीदकर लाया था. दूसरी पत्नी गंजम जिले के दिग्पाहांडी में अपने माता-पिता के पास चली गई. तब सान्या ने 300 रुपए में पात्रो की लक्ष्मी को खरीदा.

जिले के मुंडापोट्ट आदिवासियों में पत्नियों की ऐसी खरीद-फरोख्त आम बात है. भूख और गरीबी ने ही इस कुप्रथा को

सान्या ने भी उसी तरह पंचा की बेटी लक्ष्मी को 300 रुपए में खरीदा

जन्म दिया है. राज्य में भुखमरी की मार सह रहे जिले कालाहांडी के मुकाबले भी मुंडापोट्ट आदिवासियों की कहानी ज्यादा दुखभरी है. हालांकि सरकारी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं. पर स्थानीय लोगों का कहना है कि गंजम जिले में इन आदिवासियों की आबादी लगभग 10 हजार है और सभी बेहद तंगहाली में दिन गुजार रहे हैं.

राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन दोनों ने ही जैसे उनके अस्तित्व को नकार दिया है. दरअसल मुंडापोट्ट समाज से कटा हुआ घुमंतू करतबबाजों का एक समूह है. ये लोग प्रायः गांवों से थोड़ी दूर झोंपड़ियों में रहते हैं. पात्रो बताता है, "यह मुंडापोट्ट नाम तो हमें सभ्य समाज ने दिया है. इस नाम की कोई जाति नहीं. आंध्र प्रदेश में हमें साबरा नाम से जाना जाता था."

आर.एल. पटनायक

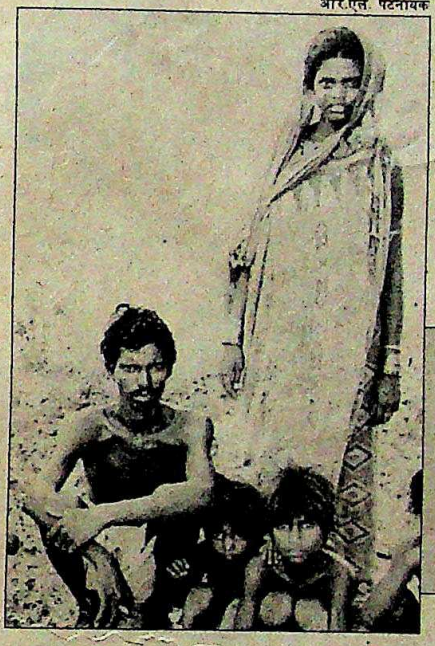

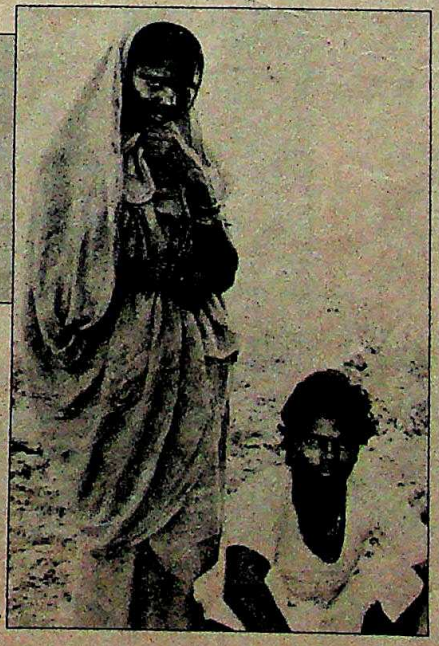

इन आदिवासियों के अनुसार उनसे कुछ पीढ़ियों पूर्व के लोग आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती जिलों से आजीविका की खोज में ओडीसा के गंजम और कोरापुट जिलों में आए थे. लेकिन ओडिया समाज में अपनी जगह बना पाने में वे सफल नहीं हुए. वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण उनके परंपरागत धंधों को बड़ा धक्का लगा. बाद में उन्होंने कलाबाजियां दिखाकर गांववालों का मनोरंजन करना शुरू कर दिया.

पांच साल पहले गरीबी से लाचार मुंडापोट्ट आदिवासियों ने अपेक्षाकृत खुशहाल आदिवासियों के पास अपनी पत्नियां गिरवी रखना शुरू कर दिया. असका से इंका विधायक राघव परीदा ने तीन साल पहले उनके बारे में ओडीसा विधानसभा में सवाल उठाए थे. तब तक मुंडापोट्ट आदिवासियों ने भूखों मरने से बचने के लिए अपनी पत्नियों को बेचना शुरू कर दिया था. परीदा ने पिछले मार्च में बजट सत्र में भी उनका मामला उठाया. लेकिन उनका बयान रिकार्ड ही नहीं किया गया. परीदा बताते हैं, "पिछले कुछ वर्षों में मैंने मुंडापोट्ट लोगों में पत्नी को बंधक रखने के तकरीबन 15 मामले पाए."

दो पत्नियों की मृत्यु और तीसरी के छोड़ जाने के बाद पंचा ने कांता को 60 रु. में खरीदा

राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारी दोनों ही किसी ऐसी जनजाति के अस्तित्व को ही जोरदार तरीके से नकार देते हैं. असका के तहसीलदार पी.सी. मोहंती ने कहा, "हमने आज तक किसी मुंडापोट्ट को नहीं देखा. ये लोग तो दरअसल खानाबदोश लोग हैं." और राज्य के मुख्यमंत्री जानकीबल्लभ पटनायक ने तो सभी तथ्यों को झुठलाते हुए वक्तव्य दिया कि "ये किस्से बिलकुल बेबुनियाद हैं क्योंकि सरकार का गरीबी हटाओ अभियान राज्य में सब जगह जोर-शोर से लागू किया जा रहा है."

लेकिन यह भी उतना ही सच है कि सरकार द्वारा इन 'किस्सों' को 'झूठा' करार दिए जाने के बावजूद कांता जैसी कितनी ही पत्नियां अगले खरीदार का इंतजार कर रही हैं. —फरजंद अहमद, असका में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

क्लिक

रघु राय

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मानसून

मिज़ाज का अंदाज मुश्किल

नई तकनीक के बावजूद मानसून का रहस्य अभी भी बरकरार

मौसम की भविष्यवाणी करने से मौसम विज्ञानी अभी भी डरते हैं. लेकिन सूखे से त्रस्त देश में बारिश के लिए बेचैनी बढ़ती जाने के साथ ही मौसम विज्ञानी मानसून के बारे में भविष्यवाणी की नई तकनीक अपनाने लगे हैं, उसका रहस्य समझते जा रहे हैं. इसी क्रम में उन्हें नई उलझनों का सामना भी करना पड़ा है. वरिष्ठ संवाददाता ***राज चेंगप्पा*** *की रिपोर्ट.*

यह विभाग ऐसी उलझी हुई जानकारी देने के लिए कुख्यात है—"पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों में हल्के बादल छाये रहेंगे और शेष भारत में अलग-अलग स्थानों पर वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ेंगे." पर पिछले पखवाड़े मौसम विभाग ने देर रात तक टीवी देखने वालों को मौसम की अ मान्य रूप से बहुत स्पष्ट जानकारियां दीं.

पूरा उत्तर भारत जिस समय गरमी झुलस रहा था और लू से मरने वालों संख्या 300 का आंकड़ा पार कर गई उसी दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभ के सचिव वसंत गोवारीकर पसीने तरबतर लोगों को ढाढ़स बंधा थे कि इस स

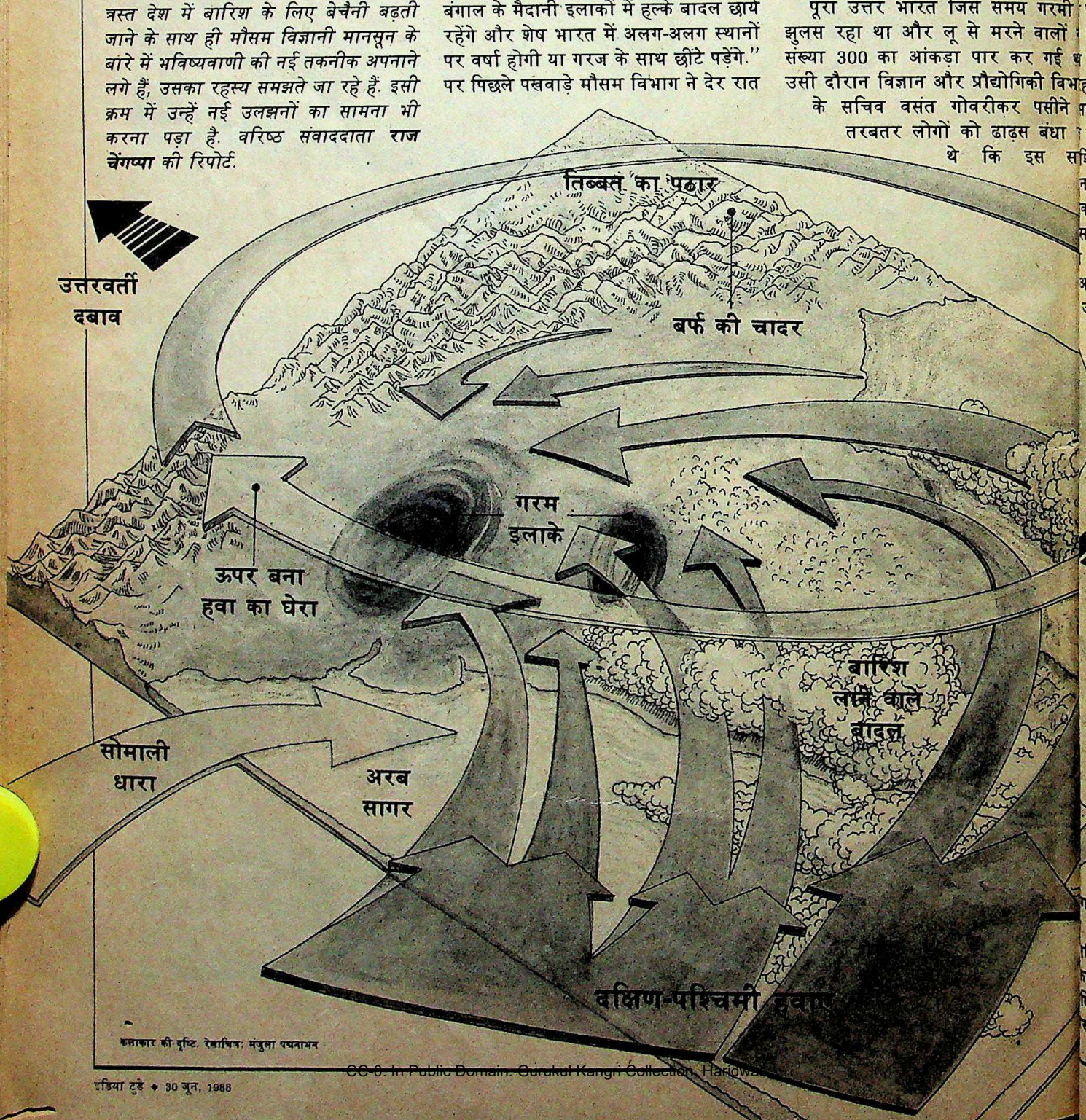

कलाकार की दृष्टि. रेखाचित्र: मंजुला पद्मनाभन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

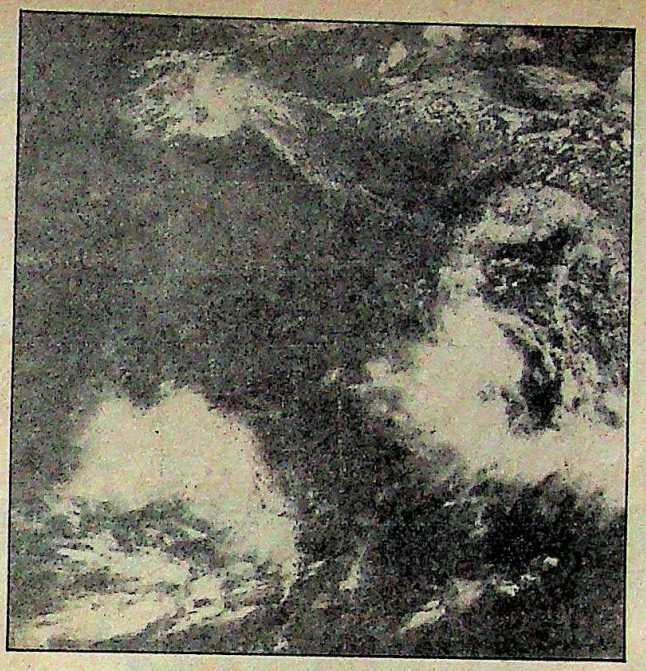

मानसून का अंदाज देता उपग्रह चित्र

...न कां बारिश अच्छी होगी. ...तनी निश्चित भविष्यवाणी से ...विज्ञानी भी सकते में आ गए. ...कभी कोई ऐसी भविष्यवाणी ...साहस नहीं कर सका है. खास ...पर इसलिए भी कि मौसम ...ग के पास उपलब्ध उपकरणों ...दिन की ही सही भविष्यवाणी ...ा सकती है. एक वैज्ञानिक के ...म की असर तो दीर्घकालिक भविष्य- ...ारियां दीं. "अभी भी एक जुआ है." इस ...य गरमी पर हाल ही के वर्षों में काफी ...ने वालों होने के बावजूद मानसून ...कर गई थ विज्ञानियों के लिए अभी भी ...गिकी विभ रहस्य बना हुआ है.

...र पसीने ...लन देश और विदेश के ...इस बंधा विज्ञानियों ने पता लगाया है ...इस सश्चिम के तटवर्ती इलाकों में ...न शुरू होने से तुरंत पहले ...क गतिज ऊर्जा की लहर-सी आ जाती ...सका पता तेज हवाओं से लगता है. ...दक्षिण अफ्रीका से आती समुद्री धारा ...अरब सागर पर असामान्य ठंड पैदा हो ...जाने की खोज भी की है. उन्होंने यह जानकारी भी हासिल की है कि देश पर 100 दिनों की अपनी सैर के दौरान मानसून सक्रिय और निष्क्रिय चरणों में ऊपर-नीचे होता रहता है. लेकिन नई दिल्ली के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के मशहूर मौसम विज्ञानी प्रोफेसर पी.के. दास का कहना है, "हम कुछ बातों का पता ही लगा पाए हैं. पहेली हल कर लेने की बात तो अभी दूर ही है."

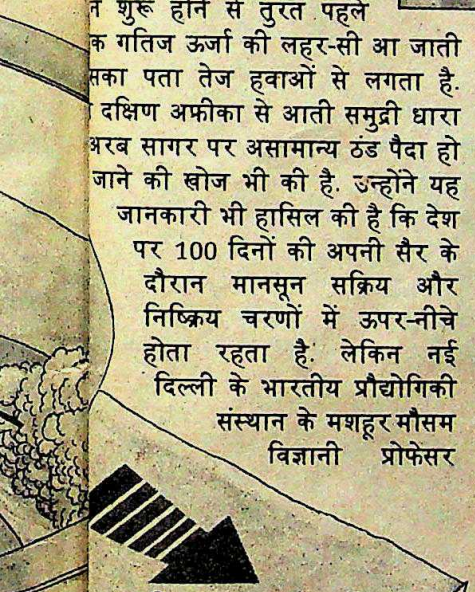

इसलिए अमूमन लीक पर चलने वाले मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दूरदर्शन कार्यक्रम में दी गई इस विस्फोटक जानकारी से हर कोई भौंचक रह गया. गोवरीकर पर आरोप लगाए गए कि वे 'बड़े बोल बोल रहे हैं.' बहस चल ही रही थी कि मानसून ने चार दिन पहले ही 26 मई को केरल के तट पर दस्तक दे दी. पर कुछ दिनों तक जब यह घनघोर घटा नहीं बनी तो मौसम विज्ञानी चिंतित हो उठे. 2 जून को जब यह उत्तर की ओर बढ़ा तो उन्होंने कुछ राहत की सांस ली.

हालांकि मौसम विज्ञानियों की यह भविष्यवाणी सिर्फ हवाबाजी नहीं थी. यह ताजा आंकड़ों के व्यापक विश्लेषण पर आधारित थी. इसके लिए गोवरीकर, पुणे के भारतीय उष्ण-कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) के निदेशक डी.आर. सिक्का और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग महानिदेशक आर.पी. सरकार, इसकी दीर्घ-कालिक भविष्यवाणी इकाई (पुणे) के वी. थपलियाल, और इसके एक निदेशक जी.एस. मंडल जैसे माहिरों की टीम जुटी थी.

इस टीम ने पता लगाया कि पिछले साल देश में भयंकर सूखा इसलिए पड़ा कि पूर्वी प्रशांत महा-सागर असामान्य रूप से गरम हो गया था. इस प्रक्रिया को 'अल नीनो' कहते हैं. अल नीनो पिछले 87 साल में सात बार हुआ है. और इन सभी मौकों पर एक साल बाद काफी अच्छा मानसून आया. पिछला साल अल नीनो वर्ष था इसलिए वे इस साल भी सामान्य बारिश की उम्मीद लगाए बैठे थे. अहम बात यह है कि उन्होंने जिन 15 प्रक्रियाओं का अध्ययन किया उनमें से 13 से अच्छे मानसून के ही संकेत मिले.

पर उनका अनुमान अभी भी पुख्ता नहीं है. अल नीनो का शायद बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ना चाहिए इस शताब्दी में यह 21 बार हुआ पर इसके बाद 12 बार मानसून सामान्य रहा. बाकी तथ्यों से भी ऐसी ही विसंगतियां जाहिर हुईं. दास बताते हैं, "हम जानते हैं कि ये सारे तथ्य मानसून में उलटफेर के लिए सिर्फ 66 फीसदी तक ही जिम्मेदार होते हैं. इसी कारण आंकड़ों पर आधारित तमाम भविष्यवाणियां अनि-श्चितता के दायरे में चली जाती हैं."

दास कहते हैं, "वहां ऊपर पता नहीं क्या-क्या चलता रहता है, बड़ी गड़बड़ियां होती रहती हैं." उदाहरण के लिए किसी दिन जब आसमान साफ हो तो चार कारक मौसम का हाल तय करते हैं—हवा, तापमान, वायुदाब और वाष्प. इन चारों में लगातार उतार-चढ़ाव होता रहता है. हर एक किलोमीटर ऊपर हवा का रुख उलटा हो जाता है और वहां जेट की गति से हवा की धाराएं चलती रहती हैं. इस अराजकता में प्रकृति जब संतुलन बनाने की कोशिश करती है तो लगता है जैसे हवा का ताप और दाब एक-दूसरे पर हावी हो जाने की होड़ करते रहते हैं.

इसी अराजकता में से मानसून पैदा होता है. यह सिलसिला तब शुरू होता है जब झुकी हुई पृथ्वी कर्क संक्रांति की ओर घूम जाती है.

कैसे घुमड़तीं हैं घटाएं

गरमी के बढ़ते जाने और एशियाई जमीन के हिंद महासागर की तुलना में अधिक गरम होते जाने से मानसून पैदा होता है. राजस्थान और मध्य भारत के ऊपर बेहद दाब वाले क्षेत्र या गरम क्षेत्र बनते हैं. फिर हवा तेजी से दिशा बदलती है और पश्चिमी हवाएं पानी बरसाने वाले बादलों को लिये आती हैं. ये हवाएं पश्चिमी तट से पार उत्तर की ओर बढ़ती हैं. मौसम विज्ञानियों ने पाया है कि अगर ऊपरी हवा की दक्षिणवर्ती होती है तो यह मानसून ले आती है. और यह भी कि हिमालय पर पड़ी बर्फ पर और तिब्बत के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र बनने का भी मानसून पर असर पड़ता है.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

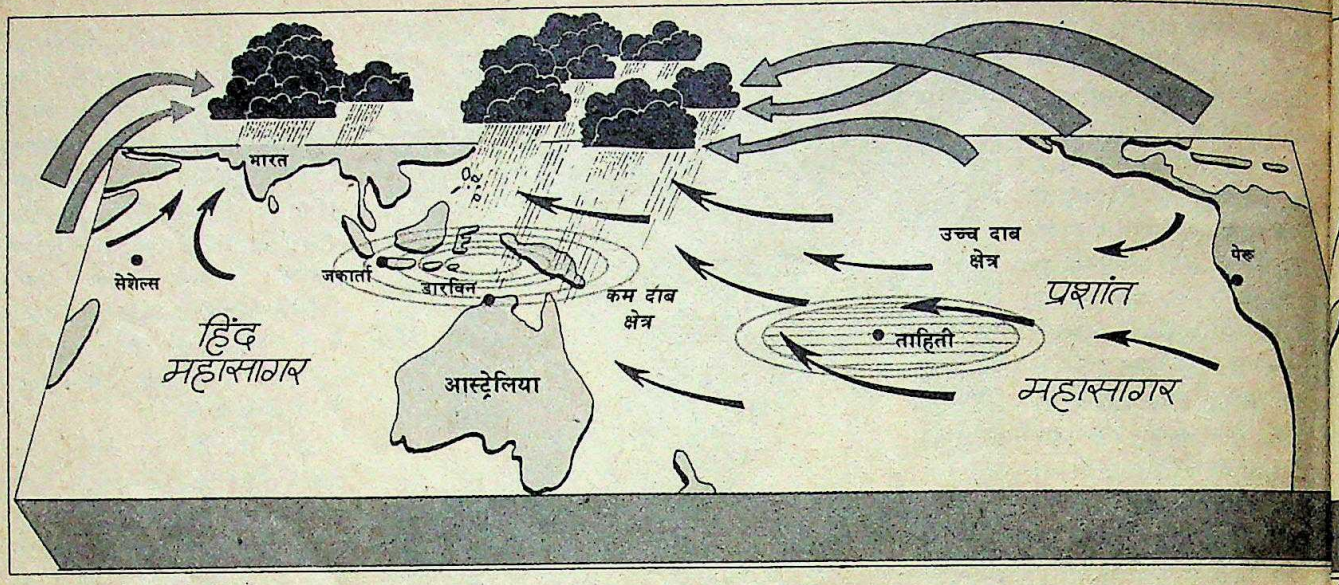

'दक्षिणी उलटफेर'

दक्षिण-पूर्व एशिया पर मानसून घुमड़ने के ठीक पहले हिंद महासागर के ऊपर का वायु दाब कम हो जाता है. इसके साथ ही दक्षिण प्रशांत महासागर में ताहिती पर यह दाब बढ़ जाता है. मानसून के हल्के पड़ जाने के बाद यह चक्र उलटा चलता है. यही उतार-चढ़ाव 'दक्षिणी उलटफेर' कहलाता है. अगर हिंद महासागर पर वायु दाब सामान्य से कम हो गया, तो इसका मतलब है कि भारत पर मानसून अच्छा गुजरेगा. कुछ मौसम विज्ञानियों का मानना है कि इसके ठीक पहले अल नीनो नाम का असामान्य उतार-चढ़ाव वायु दाब का असंतुलन पैदा कर देता है.

और जैसे ही गरमी उत्तरी गोलार्ध (जिसमें भारत भी है) में पड़ने लगती है तो एशिया की जमीन समुद्र से ज्यादा तपने लगती है.

इस अंतर की वजह से राजस्थान, पाकिस्तान और सऊदी अरब के रेगिस्तानी इलाकों के ऊपर कम दाब का केंद्र बन जाता है. इससे हवाओं का रुख नाटकीय ढंग से उलट जाता है. वे उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम की ओर बढ़ने लगती हैं. ये दक्षिण-पश्चिमी हवाएं अपने साथ घनघोर घटाएं लाती हैं, जो सबसे पहले पश्चिमी तटों पर घुमड़ती हैं, फिर धीरे-धीरे उत्तर की ओर बढ़ती हैं. इन हवाओं की पूर्वी धाराएं हिमालय से टकराती हैं और फिर मैदानी इलाकों की ओर बढ़ जाती हैं. ठंड शुरू होते ही मानसून मैदान छोड़ने लगता है.

यह सिलसिला देखने में तो बहुत आसान लगता है, पर एक मौसम विज्ञानी के मुताबिक अब, "हम भी झूलने, गड़बड़ाने लगे हैं." ये हवाएं आम तौर पर मार्च में राजस्थान, मध्य भारत और पूर्वी तटवर्ती इलाकों के ऊपर के तापमान को नियंत्रित करके मानसून की ताकत तय करते हैं. उन्होंने पाया है कि इन गरम इलाकों का तापमान जब भी सामान्य से ज्यादा होता है तो—जैसा कि यह इस साल था—मानसून बेहतर होता है. लेकिन अक्सर ऐसा भी हुआ है कि इन हालात के बावजूद मानसून कमजोर होता है. यानी अटकलें लगाने के सिवा चारा नहीं.

मानसून की भविष्यवाणी के बेहतर संकेतों की तलाश में लगे वैज्ञानिकों ने जितने जवाब ढूंढ़े हैं उनसे ज्यादा सवाल खड़े हो गए हैं. इसके लिए 1979 में मानसून प्रयोग (मोनेक्स) हुआ था, जिसमें 140 देशों ने भाग लिया था. तब बरसात से ठीक पहले भारत के पश्चिमी तट पर ऊर्जा के नाटकीय विस्फोट की बात पता लगी थी. आठ साल के बाद भी वैज्ञानिक इस विस्फोट की संतोषप्रद वजह नहीं पता कर सके हैं.

अब वे तिब्बत के पठार पर भी ध्यान दे रहे हैं. परंपरा के मुताबिक हिमालय पर जमी बर्फ की परत पर अभी भी नजर रखी जाती है क्योंकि यह माना जाता है कि इसकी परत जितनी मोटी होगी, मानसून उतना ही खराब होगा. पर तिब्बत का पठार क्योंकि समुद्र की सतह से पांच हजार फीट ऊंचा है इसलिए वायुमंडल की कई विसंगतियां पैदा करने वाली भट्ठी की तरह काम करता है.

मौसम विज्ञानी मानते हैं कि बहुत-सी अबूझी प्रक्रियाओं के रहस्य तिब्बत के पठारों से उजागर हो सकते हैं. वे सिर्फ इतना जानते हैं कि हवा की दो बेहद तेज धाराएं या तेज हवा की दो संकरी पट्टियां देश के ऊपरी वायुमंडल को आड़ी-तिरछी काट हुई गुजरती हैं. मई आते-आ पश्चिमी जेट धारा हिमालय ढलानों से टकराकर अचा उत्तर की ओर मुड़ जाती कहा जाता है कि यह तिब्बत पठार की वजह से ही होता जैसे ही हिमालय वाली ध घूमती है, पूर्वी जेट ध दक्षिणी प्रायद्वीप पर पहुंच ज है और तब तक वहीं जमी र है जब तक मानसून कमज नहीं पड़ जाता.

मानसून लाने में इन जेट धाराओं भूमिका अभी साफ नहीं है, जबकि वैज्ञा उनसे कुछ किलोमीटर नीचे बनने असीमित उच्च दाब या चक्रवातरोधी क्षेत्र अध्ययन कर रहे हैं. इस उच्च दाब क्षेत्र घेरा आम तौर पर दक्षिण गोवा तक पहु है. विज्ञानियों ने पता लगाया है कि अगर जरा-सा दक्षिण की तरफ घूमकर कर्नाट कारवाड़ की तरफ पहुंच गया तो यह मान के लिए माकूल नहीं होगा. इसका क शायद यह है कि उच्च दाब वाला क्षेत्र के विशालकाय गोले' की तरह काम कर जो दक्षिण-पश्चिमी मानसून को पश्चिमी तट पर घुमड़ने से रोक देता है. मिसाल तौर पर इस साल यह सही स्थिति में नहीं इसी वजह से गोवरीकर की आशावादिता बावजूद कई वैज्ञानिकों को मानसून के होने पर शक है.

एक और विचित्र बात 70 के दशक पता लगी. वह यह कि मानसून के आ पहले अरब सागर की सतह का ता तीन-चार डिग्री सेल्शियस तक गिर जात यह गिरावट 'सोमाली धारा' नामक प्र

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

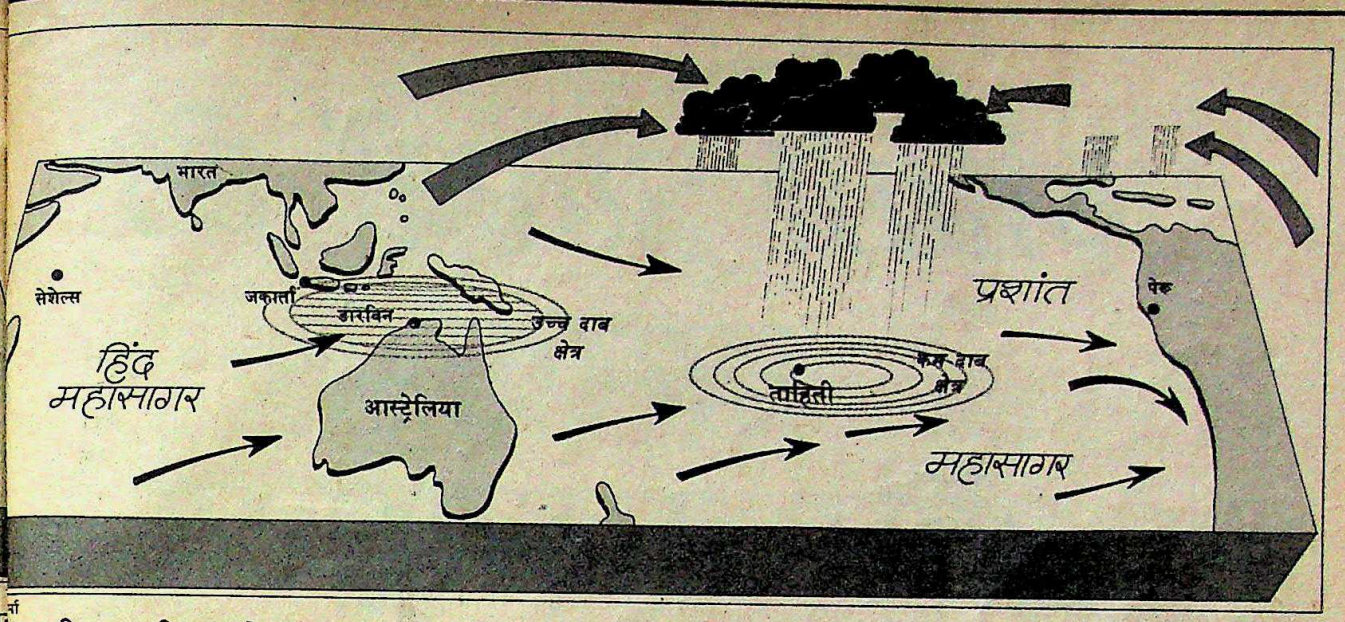

अल नीनो की बात

पिछले साल भारत में सूखे का कहर ढाने वाला अल नीनो अपने आपमें बहुत मासूम है. यह पूर्वी प्रशांत महासागर पर बना उच्च दाब का क्षेत्र है जिसका काम है इंडोनेशिया की तरफ कम दाब के इलाके में हवाएं चलाना. पर हर चार से सात साल में कम दाब का यह क्षेत्र प्रशांत महासागर के बीचोबीच पहुंच जाता है. हवाएं लड़खड़ाती हैं और उनके रुख बदल जाते हैं. इससे पेरू के 18,000 किमी के समुद्र तट पर गरम समुद्री पानी छा जाता है. नतीजतन उत्तरी अमेरिका में बाढ़ आती है और अफ्रीका, एशिया व आस्ट्रेलिया के कई हिस्सों में सूखा पड़ता है.

समुद्री धारा की वजह से
है जो पूर्वी अफ्रीका से शुरू
है. इस धारा के कारण
महासागर का ठंडा पानी
सागर की ओर बहने
है. और तापमान की कमी
पर असर डालती है.
मानसून पर विश्वव्यापी
चक्र का भी असर पड़ता
र मानसून के भारत पर
से पहले ही हिंद महा-
पर वायु दाब गिर जाता
क उसी दौरान 10,000
मीटर दूर दक्षिण प्रशांत महासागर में
ी पर दाब बढ़ जाता है. बरसात जब
पड़ने लगती है तो यह चक्र उलटा होने
है. इसे 'दक्षिणी उलटफेर' कहते हैं. यह
पश्चिमी मानसून का संकेत देने वाला
कारक है. इस साल हिंद महासागर पर
सामान्य से कम है, इसे भारतीय
ों के लिए शुभ संकेत माना जा रहा है.
ी में जब मौसम विज्ञानियों ने यह
पेश किया कि यह 'दक्षिणी उलटफेर'
नो का जनक है तो इसके बाद से इस
फी शोध शुरू हो गया है. दुनिया के
की फिजां तय करने में अल नीनो की
अव्वल मानी जाती है और यह काफी
रे बनता है. आम तौर पर दक्षिण
पर उच्च दाब के कारण इंडोनेशिया
न दाब वाले क्षेत्र की ओर हवाएं बह
. हर चार से सात साल में यह चक्र
चल पड़ता है.
पहले कम दाब का क्षेत्र प्रशांत में
पर पहुंचता है; हवाएं लड़खड़ाती हैं
नका रुख पलट जाता है. तब गरम
ी धाराएं पेरू के 18,000 किलो-
मीटर चौड़े समुद्रतट पर छा जाती है. इसके नतीजे तबाही मचा देने वाले होते हैं. इस गरम पानी से पेरू के समुद्रतट की मछलियां खत्म हो जाती हैं, उत्तरी अमेरिका में बाढ़ आ जाती है और भारत, आस्ट्रेलिया व अफ्रीका के कुछ हिस्सों में सूखा पड़ता है.

अल नीनो और भारत के सूखे का रिश्ता सबसे पहले 1980 में आईआईटीएम के सिक्का ने पता लगाया था. वे बताते हैं, "इस भौतिक विज्ञान के बारे में अभी भी संशय हैं. लेकिन हमें यह मालूम है कि मानसून सिर्फ अल नीनो पर ही निर्भर नहीं है. एक अच्छा मानसून अल नीनो की भ्रूण हत्या कर सकता है. इसलिए अब यहां मुर्गी और अंडे वाला सवाल खड़ा हो गया है."

कुछ विज्ञानियों ने जब यह देखा कि पेरू के तट पर समुद्र का तापमान गिरकर सामान्य के आसपास हो गया है तो उन्होंने अच्छे मानसून की भविष्यवाणी कर दी. पर तापमान की यह गिरावट अचानक रुक गई और अल नीनो आश्चर्यजनक रूप से 18 महीने तक बना रहा. नतीजतन भारत को इस सदी का सबसे भयंकर सूखा झेलना पड़ा.

इन्हीं वजहों से मानसून की भविष्यवाणी जोखिम बन जाती है. और किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हवा की विश्व-व्यापी गति, तापमान, दाब व घुमड़ते बादलों के आंकड़ों पर विचार करना बेहद जरूरी हो जाता है. मानसून के विभिन्न संकेतों के बीच तालमेल ढूंढने के लिए विश्लेषण और जोड़-घटाव की असीमित क्षमता की जरूरत है. मिसाल के लिए मौसम विज्ञानियों ने दुनिया को विशालकाय आयताकार क्षेत्रों में बांट दिया है जिनमें 10,000 बिंदु हैं. 24 घंटों का मौसम जानने के लिए हर बिंदु पर एक लाख गणनाएं करनी पड़ती हैं.

नवंबर में अमेरिकी सुपर कंप्यूटर आने के बाद और थोड़े अरसे के लिए मौसम की भविष्यवाणी करने वाला राष्ट्रीय केंद्र बन जाने से भविष्यवाणी करने की क्षमता बढ़ जाएगी. पर मानसून की भविष्यवाणी के लिए उपयुक्त मॉडल बनाने में सालों लग जाएंगे.

इस बीच मौसम विज्ञानियों के बीच आजकल धोबी और गधे का एक किस्सा काफी लोकप्रिय हो गया है. किस्सा है कि धोबी राजा के पास गया और उसने कहा, "आज बारिश होगी क्योंकि मेरे गधे का दायां कान फड़क रहा है." इस पर राजा हंसने लगा. पर उस दिन बारिश हो गई. राजा खुश हुआ और उसने शहर में धोबी और गधे के रहने का बहुत बढ़िया इंतजाम करा दिया. नतीजा यह हुआ कि तब से हर गधा यह सोचने लगा है कि वह मौसम की भविष्य-वाणी कर सकता है.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

राज कपूर

नीली आंखों के सपने और सचाइयां

राज कपूर को अपने मुर्गे-मुर्गियों से बहुत प्यार था. जैसे ही वे चेंबूर के अपने बंगले के हरे-भरे मैदान में पहुंचते, ये सब उन्हें घेर लेतीं और दाने के लिए शोर मचाने लगतीं. राज कपूर उन्हें दाना भी देते और देर तक उनसे बातें भी करते. लेकिन 3 जून को वे शोर मचाती रहीं और उन्हें पुचकारने-दुलारने वाला खामोश रहा. उन्हें क्या पता कि उनका हमदर्द हमेशा के लिए खामोश हो गया है.

राज कपूर का शव वातानुकूलित कमरे में रखा था जहां उस धूल का नामो-निशान नहीं था जो अंततः उनके लिए जानलेवा साबित हुई. उनके चेहरे का गुलाबी-पन जर्द हो गया था. आठ डॉक्टरों की मदद से महीने भर तक उन्होंने जीवन के लिए जो संघर्ष (देखें बॉक्स) किया उसने उनके चेहरे की आभा छीन ली. लगातार सुबक रहे धर्मेंद्र ने कहा, "वो गुलाबी रंग काला पड़ गया है."

राज कपूर की मौत का यह सबसे हृदय विदारक पहलू था. उनकी मृत्यु अनपेक्षित नहीं थी. रोज-रोज के स्वास्थ्य बुलेटिनों ने इसका एहसास तो करा दिया था फिर भी पूरा फिल्मोद्योग किसी फिल्मी चमत्कार की आस लगाए बैठा था. इसलिए उन्हें जो सदमा पहुंचा वह वास्तविक था. एक के बाद एक अभिनेता जिस तरह राज कपूर के शव से लिपटकर रो पड़ता वह अपने आप में उस सदमे और शोक का सबूत था.

वहां की मनहूस खामोशी कभी किसी के सुबकने की आवाज से, कभी कैमरे की क्लिक से और कभी शशि कपूर की बेटी संजना के कदमों की आवाज से टूट पडती. संजना वहां आने वालों को लगातार छह घंटे तक चाय-पानी पिलाती रहीं. रीमा कपूर अपने दुख को बड़े धैर्य के साथ संभाले हुए इस कमरे से उस कमरे में आ जा रही थीं. ऋषि कपूर शांत रहते हुए अपने छोटे भाई राजीव कपूर को

सभी फोटो: नामस भोजानी

राज की रोती-बिलखती विधवा कृष्णा कपूर को संभालतीं उनकी बेटियां

शांत कर रहे थे जो अखबारवालों की दखलंदाजी से नाराज हो पड़ते. शशि कपूर भी अपने संयम का परिचय देते हुए दरवाजे पर खड़े थे और आने-जाने वालों को देख रहे थे. कृष्णा अपने पति के शव के पास बैठी थीं. और संन्यासीनुमा भव्य दाढ़ी में खड़े थे शम्मी कपूर, जो तय कार्यक्रम के अनुसार सब कुछ संचालित करवाने में लगे थे.

कुमार गौरव आर.के. स्टुडियो में मौ
राज कपूर की एकमात्र बड़ी तस्वीर ले अ
थे जो शवगाड़ी के आगे लगाई जानी
अंतिम यात्रा आर.के. स्टुडियो होते हुए चे
शमशान घाट तक होनी थी. दिलीप कु
उदास बैठे थे.

सफेद लिबास में सजी औरतें राज क
को प्रिय थीं. और उस दिन प्रायः सभी औ
सफेद साड़ी या सलव
कमीज में थीं. डिंपल ध
धीरे नादिरा से बात
रहीं थीं, जिनकी लाल अ
बता रहीं थीं कि वे
भर सो नहीं पाई हैं. नादि
ने कहा, "अब मैं
अकेलापन महसूस कर
हूं." डिंपल ने कहा, "स
में नहीं आ रहा कि
कहूं." रेखा रंगीन च
लगाए एक कोने में बैठी
वे राज कपूर के शव
देखना नहीं चाहती
"मैंने उन्हें हमेशा जी
और उत्साह से भरा
है." उनके पास ही एक
मायूस और थकी दिख रही सिमी बैठी

पूरे माहौल में राम धुन गूंज रही थी.
अचानक बाहर की हलचल ने अंदर
खामोशी तोड़ी. श्रीनगर में शूटिंग छोड़
अमिताभ बच्चन आए. छड़ी के सहारे च
हुए वी. शांताराम भी आए.

जब रणधीर, ऋषि, राजीव, शम्मी, श
अमरीश पुरी, सतीश शाह और राजन
अर्थी लेकर बाहर आए तो भीड़ में हल
बढ़ गई. बच्चे तो वहां मौजूद फिल्मी सि
को ही देखकर खुश थे लेकिन उनके

शवया

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

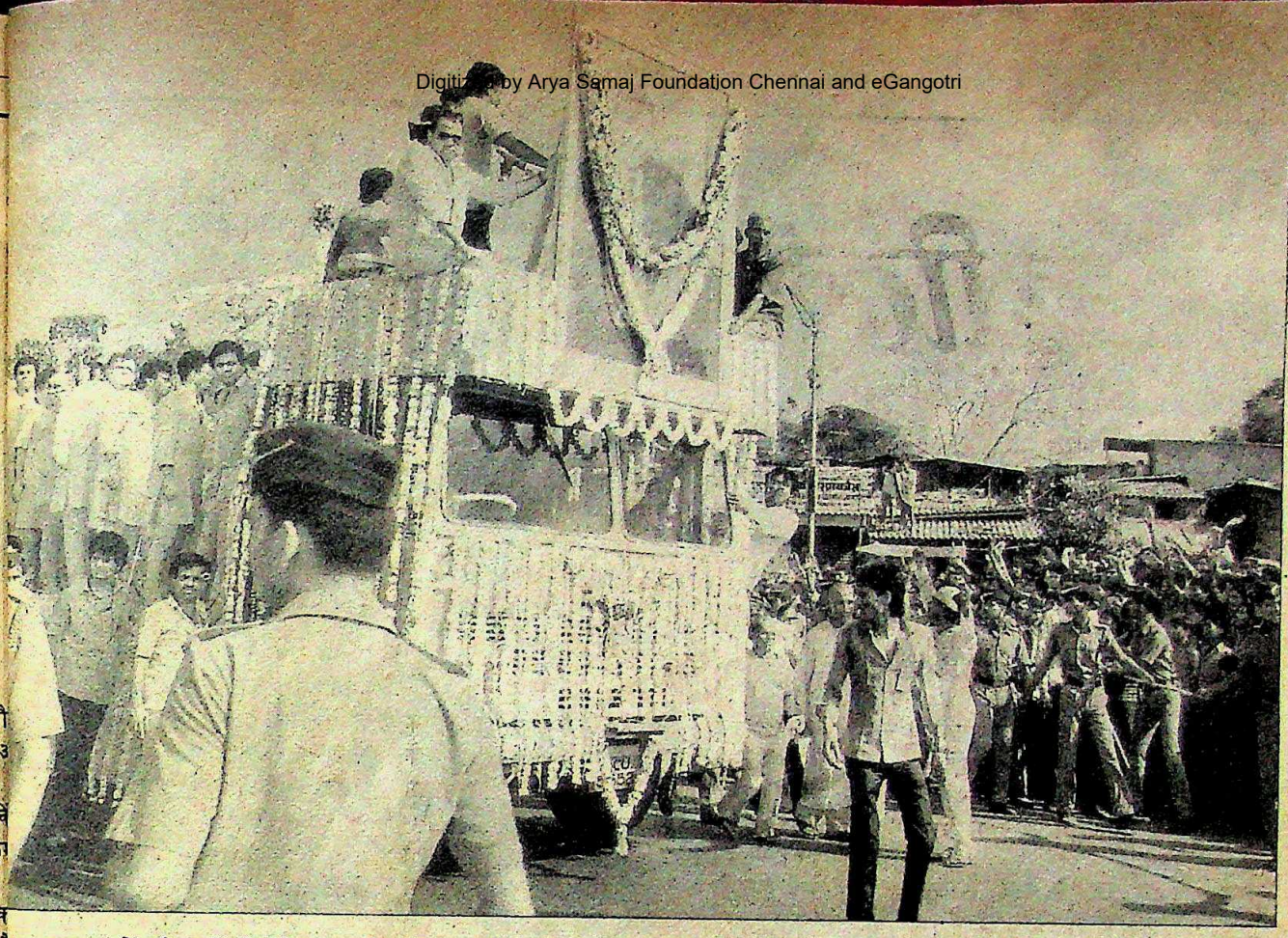

शवयात्रा में भीड़ को नियंत्रित करती पुलिस; और (नीचे बाएं से) अर्थी को कंधा लगाए ऋषि, रणधीर और अमरीश पुरी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पिता एक गहरे गम में डूबे हुए थे.

शव के साथ चलने वालों में कपूर खानदान के लोगों के अलावा राजेश खन्ना, मनोज कुमार, अमरीश पुरी, राजेंद्र कुमार, राज बब्बर, प्रेम किशन, प्रेम चोपड़ा और राजिंदर नाथ शरीक थे. जब शवगाड़ी मेन रोड की ओर बढ़ी तो एक अजीब दृश्य उपस्थित हो गया. सैकड़ों स्त्री-पुरुष और बच्चे भी कारों के काफिले के साथ दौड़ पड़े. रास्ते के दोनों ओर मकानों की छतों, खिड़कियों और गैलरियों में ठसाठस लोग खड़े थे.

वैसे सभी ने राज कपूर का गुणगान ही नहीं किया. 1949 में 'आवारा' के निर्माण के बाद से लगातार 37 वर्षों तक आर.के. स्टु-

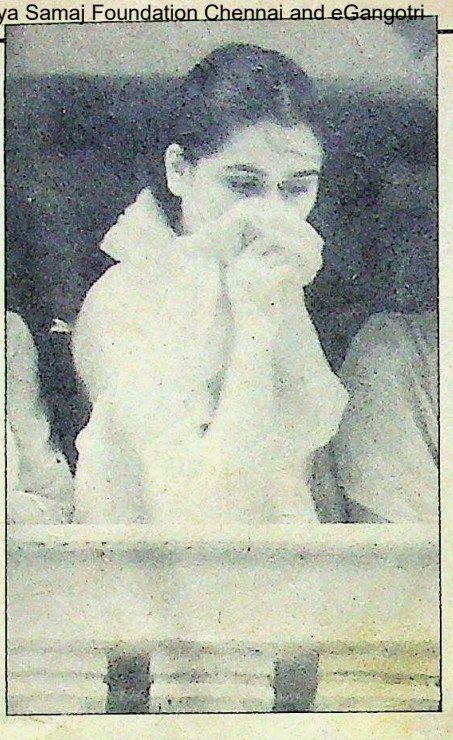

(दाएं) आंसू पोंछतीं पद्मिनी कोल्हापुरे; बिलखते रणधीर कपूर; और (नीचे बाएं से) ऋषि, शशि, प्रेम चोपड़ा, दिलीप कुमार, शम्मी और राजीव

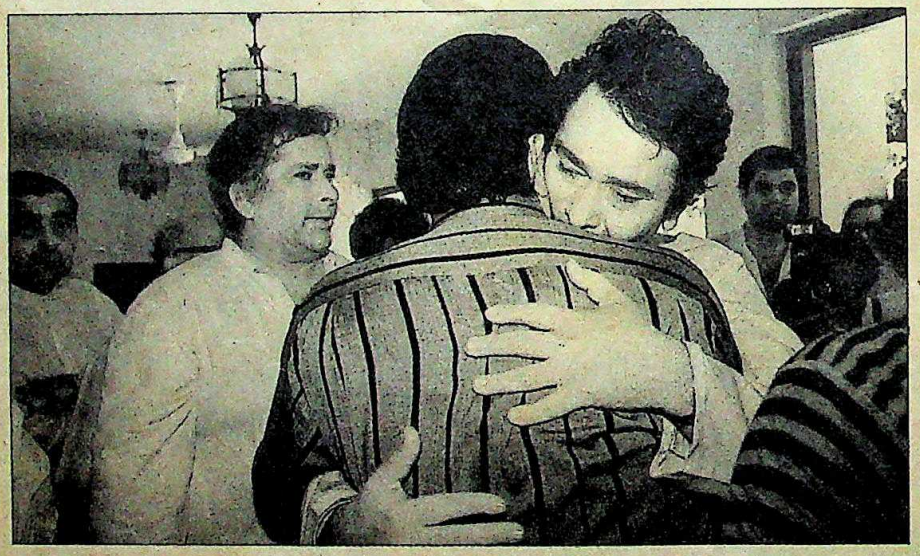

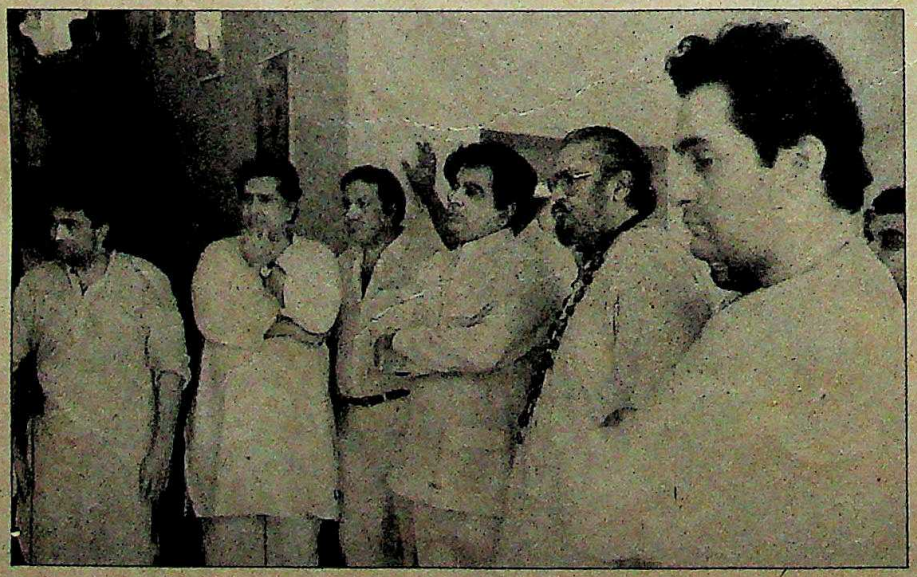

डियो में काम करने वाले राज रतन ने क
"वे अच्छे आदमी थे, पर चालाक भी
1973 के पहले उनका व्यवहार बहुत अ
था लेकिन जब हम लोगों ने झंडा उठा
('बॉबी' के बाद 1974 में स्टुडियो के ब
कारीगरों ने यूनियन बनाई जिसमें अन्य क
चारी भी शामिल हुए. इसके बाद उनसे क
तोड़ लिया गया और उन्हें दिहाड़ी पर क
मिलने लगा) तो उन्होंने हमें पैसा दिया
छोड़ दिया." दूसरे कर्मचारी केशव जाधव
कहा, "हमारा क्या होगा, हमें पता नहीं
पता नहीं उनका कोई भाई स्टुडियो चलाने
दिलचस्पी रखता है या नहीं." विडंबना
थी कि अंतिम संस्कार के वक्त आर.के.
डियो के बहुत कम कर्मचारी मौजूद थे.

हां, शिवसेना के लोग भी नदारद
इसके नेता बाल ठाकरे सुबह बंगले पर
थे पर चेंबूर में तीन दशकों तक गण
जुलूस का नेतृत्व करने वाले राज कपूर
शवयात्रा में सेना के कुछ ही झंडे नजर

इसके विपरीत इंका ने सम्मान की

इलाज

शानदार संघर्ष

उस दिन 4 मई को नई दिल्ली
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान
(एआईआईएमएस) के तंत्रिका विज्ञा
के सघन चिकित्सा कक्ष (आईसी
कदम रखते ही प्रधानमंत्री राजीव ग
कदम ठिठक से गए, चेहरा गमगीन
कक्ष के पांच में से एक बिस्तर
मरीज का चेहरा देखकर वे विचलि
गए. गुलाबी गालों वाले इस शख्स क
किलोग्राम वजनी शरीर सुन्न-सा प
कम-से-कम 20 इलेक्ट्रोड लाइनें
जिस्म से जुड़ी हुई थीं. कंप्यूटर के
पर उभर रहा संदेश उसकी श
दुरावस्था का ही संकेत दे रहा था.
को घेरे खड़े डॉक्टरों के चेहरे भाव

64 वर्षीय राज कपूर लाइलाज
से जूझ रहे थे. 'एडल्ट रेसपिरेटरी
सिंड्रोम' (आर्ड्स) नामक श्वास की
ने एक के बाद एक उनके सभी अ
निष्क्रिय कर दिया था. और उनकी
जो आखिरी स्वास्थ्य बुलेटिन जारी
गया उसमें बस इतना लिखा था—क
की पूर्ण निष्क्रियता के कारण हृद
श्वास गति के बंद होने से उनकी मृ

मृत्युशैया पर पड़े होने के बावज
कपूर बीमारियों से बखूबी जूझते रहे

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कर दी. केंद्रीय सूचना व प्रसारणमंत्री कृशन लाल भगत ने, जो स्वास्थ्य राज्य-सरोज खापर्डे सहित शव के साथ ई विमान से आए थे, कहा, "हाल में मैं त महोत्सव के सिलसिले में सोवियत संघ था. वहां हर आदमी—विद्यार्थी, बच्चे, ं और राजनेता— ने हमें रोका और कपूर के स्वास्थ्य के बारे में पूछा. एक बच्ची ने तो हमें राज कपूर का एक भी सुनाया." अंतिम संस्कार के समय ाष्ट्र के कुछ मंत्री भी उपस्थित थे. सुबह मंत्री शंकरराव चव्हाण परिवार के लोगों लकर गए थे. राजीव गांधी के दोस्त चोपड़ा ट्रक में शव के पास खड़े दिखे. ने कहा, "मैं निजी हैसियत से आया हूं." छ देर पहले जो बादल छा गए थे वे छंट रणधीर कपूर ने जब चिता को अग्नि दी ाम का सूरज अपनी पूरी तेजी के साथ आया था. 'राम नाम सत्य है' के रण के बीच ही घंटे भर के अंदर राज का शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया

था. पीछे रह गया तो सिर्फ उनका हैरतअंगेज फिल्मी जीवन, जिसमें उन्होंने नारी रूप की आराधना की थी, जिसमें वे दलितों का प्रतीक बनकर उभरे थे, जिसमें उन्होंने शानदार संगीत की सृष्टि की थी और अपनी कल्पना से जबरदस्त रंग भरा था.

उनकी मृत्यु फिल्मोद्योग की एक बड़ी हस्ती की मृत्यु भर नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति का निधन है जो इस उद्योग के हर रंग का प्रतिनिधि था चाहे वह मस्ती और धूमधड़ाके का रंग हो या मोहब्बत और आंसू का या उत्तेजना और भावोन्मत्तता का, या सबसे बढ़कर करुणा का.

चार दशकों तक राज कपूर देश की धड़कन पर राज करते रहे. उनकी लापरवाह अदाएं लोगों के दिलों में बस गई थीं. वे एक ऐसे आम, गंवई हिंदुस्तानी का प्रतिरूप बन गए थे जो कभी भी बुरे ख्यालों को अपने पास फटकने नहीं देता बल्कि 'इस्स' कहकर उसे उड़ा देता, जैसा कि 'तीसरी कसम' में वे करते हैं. गांव से शहर में कुछ बनने को आया नौजवान स्वप्नलोक की परी से प्रेम करता है, एक छाते के नीचे उसके साथ मिलकर गाता है, "प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल." और शहर की सड़कों की हल्की रोशनी में इस रूमानी जोड़ी की छवि देखने वालों को सम्मोहित कर लेती है. विशुद्ध फंतासी है यह लेकिन राज कपूर की सफलता इसे विश्वसनीय बना देने में ही है.

खालिस राज कपूर मार्का फिल्मों में एक छद्म समाजवादी संदेश भी होता था. साथ ही अविस्मरणीय संगीत, खूबसूरत हीरोइन और भरपूर मनोरंजन के कारण उनकी फिल्में जबरदस्त लोकप्रिय हुईं. आज किसी बड़ी हिट फिल्म के लिए तरसता फिल्मोद्योग राज कपूर के जादुई करिश्मे के प्रति नत-मस्तक-सा है जिसने 1985 में भी 'राम तेरी गंगा मैली' जैसी हिट फिल्म बना दी थी. केंद्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड के अध्यक्ष विक्रम सिंह कहते हैं, "वे एकदम गैर बौद्धिक चीज से भी दर्शकों को मंत्रमुग्ध किए रह

ी रोगों के विशेषज्ञ प्रोफेसर जे.एन. का कहना था, "जिस हालत में उन्हें लाया गया था यदि कोई और मरीज तो शायद 48 घंटों में ही मर जाता." डॉक्टरों के उस दल के अगुआ हैं जो ने एक महीने से उनके परिवार के यों के साथ इस शोमैन की जिंदगी और की लड़ाई में शरीक रहे.

मई को दादा साहब फाल्के पुरस्कार ण समारोह के दौरान हालत बिगड़ की वजह से उन्हें संस्थान में भर्ती गया. उस वक्त वे श्वास नली में ट के कारण गंभीर अवस्था में थे. उनके साथ चलने वाला ऑक्सीजन भी ज्यादा कारगर साबित नहीं हुआ स्थान के एनेस्थेटिस्ट डॉ. एस. एस. को उन्हें कुछेक घंटों के भीतर ही श्वास पर रखना पड़ा. कृत्रिम श्वास ब उनका शरीर बरदाश्त नहीं कर तो उन्हें तनावमुक्त करने की दवाइयां कृत्रिम फेफड़े पर रखे जाने वाले 50 मरीजों की प्रायः मौत हो जाती है. ए पूरे महीने राज कपूर के स्वस्थ होने इतनी ही उम्मीद बाकी रही थी. र्ड्स' काफी बढ़ गया था और उनके सामान्य तौर से शरीर के अंगों को ल रखने के लिए जरूरी ऑक्सीजन ीच पा रहे थे. पहली बार जब खून च की गई तो उसमें पारे का स्तर 60 गया जबकि सामान्य 550 माना जाता है. तेज खांसी, दमा और मधुमेह ने हालत और खराब कर दी.

दरअसल, राज के जिस्म की हर हरकत पर निगरानी रखी जा रही थी. उनकी धमनियों, शिराओं, हवा के दबाव, श्वास दर, ऑक्सीजन लेने की मात्रा, हृदय गति, रक्त में ऑक्सीजन के स्तर और यहां तक कि उनकी सांस से बाहर निकली कार्बन डाई ऑक्साइड की मात्रा जांचने के लिए भी उपकरण लगाए गए थे.

पांडे कहते हैं, "यह बेहद मुश्किल काम था और हमने पहले हफ्ते से ही सघन चिकित्सा शुरू कर दी थी." उपचार के नए तरीके ब्रोंकोस्कोपी और ब्रोंकियल वाशिंग इस्तेमाल किए गए जिनमें रुकावट हटाने और फेफड़ों को ज्यादा ऑक्सीजन खींचने योग्य बनाने के लिए लवण के घोल से उन्हें साफ किया जाता है. इससे रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा में बढ़ोतरी हुई. और एक वक्त तो कृत्रिम ऑक्सीजन की मात्रा 100 फीसदी से घटाकर 35 फीसदी कर दी गई. डॉक्टर चाहते थे कि वे खुद सांस लेना शुरू कर दें. लेकिन एक और जटिलता पैदा हो गई. उनके फेफड़ों की मांसपेशियां इतनी कमजोर हो गईं (जो विरले ही होता है) कि उन्होंने काम करना ही बंद कर दिया. और यांत्रिक तरीकों से उनकी सांस जारी रखनी पड़ी.

साथ ही साथ उनके दूसरे अंग भी अब जवाब देने लग गए थे. उनके गुर्दे में खराबी आ गई और पेशाब बंद हो गया. इस बीमारी के विशेषज्ञ डॉ. के.के. मल्होत्रा बुलाए गए और उन्होंने राज कपूर को चार बार डायलिसिस पर रखा.

लेकिन इस लड़ाई में हार साफ दिखाई दे रही थी. उनके शरीर की अमूमन सभी प्रणालियां कृत्रिम उपायों पर निर्भर थीं. उनके फेफड़े श्वास यंत्र पर, गुर्दा डायलिसिस पर, हृदय पेसमेकर पर. लेकिन यकृत के काम बंद करने पर ज्यादा कुछ करना संभव नहीं रह गया था.

उस मनहूस दौर में एक ही बात थी जो राहत देती थी, वह यह कि मृत्यु के तीन दिन पहले तक राज कपूर होश में रहे. करोड़ों लोगों के होठों पर मुस्कराहट बिखेर देने वाला शख्स हर सुबह डॉक्टरों के आने पर बड़े यत्न से किसी तरह मुस्करा उठता था. कभी ध्वनि विस्तारक की मदद से वे अपने परिवारवालों से पंजाबी में बात भी करते.

आखिरी दिनों में सघन कक्ष के प्रभारी डॉ. एस.एस. सैनी ने दिल्लगी में राज कपूर से पूछा कि क्या वे अपनी अगली फिल्म में भीड़भाड़ के किसी दृश्य में उन्हें शामिल करेंगे, राज ने इनकार में सिर हिला दिया था. सैनी ने खुशामद की तो राज कपूर ने उन्हें अपने पास बुलाया और कान में फुसफुसाकर कहा, "हीरो, हीरो!" करोड़ों लोगों के दिलों में बसे इस 'जोकर' का शायद यह आखिरी मजाक था.

—पंकज पचौरी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

यादें

हरदिल अजीज दोस्त की दास्तां

राज कपूर की 39 वर्षीया बेटी रितु नंदा कहती हैं, "एक महीने तक उन्होंने हम सबको बेहद चिंतित रखा. यह लड़ाई भगवान और विज्ञान के बीच थी, जिसमें आखिर भगवान ही जीते."

अस्पताल में रहते-रहते कपूर खानदान के सदस्यों ने अरसे बाद एक बार फिर रिश्तों में आत्मीयता की गरमाहट महसूस की. जिस अंतरगता से वे एक साथ रहे, वैसे पहले कभी नहीं रहे. उनकी छोटी बेटी 31 वर्षीया रीमा कहती हैं, "सबसे दुखद तो यह था कि वे बात नहीं कर पाते थे." लेकिन अपनी आंखों, अपने हाव-भाव, मुस्कान और आंसुओं से वे अपनी बात कह देते थे. बेहोश होने से एक दिन पहले रितु ने उनसे पूछा कि क्या वे संगीत सुनना पसंद करेंगे तो उन्होंने सहमति में सिर हिला दिया था. रितु ने उनके सिर पर इयरफोन लगाकर 'आवारा हूं...' गीत बजा दिया था. रितु बताती हैं, "उनकी आंखों से आंसू बह चले थे."

जब उनके सामने आवाज तेज करने वाली मशीन (वायस एकटीवेटर) रखी गई तो पहला शब्द उन्होंने जो बोला वह था—कृष्णा. उनकी पत्नी कृष्णा कपूर ने समझा कि वे शायद भगवान कृष्ण को याद कर रहे हैं. लेकिन नहीं. राज कपूर ने पत्नी की ओर देखा मानो कह रहे हों कि मैं तुम्हारा नाम ले रहा हूं. और उनकी आंखों में आंसू की एक बूंद चमक गई.

और रुमानी तबीयत के तो वे थे ही. रीमा के साथ किसी बात पर यदि उनकी झड़प हो जाती तो वे उनके पास एक पर्ची लिखकर भिजवाते, "जब मैं नहीं रहूंगा तो तुम मुझे याद करोगी. मैं तुम्हारे पास हूं, इसीलिए तुम्हें मेरी परवाह नहीं." रीमा बताती हैं, "इस तरह भावनाओं को भुनाना उन्हें खूब आता था."

रीमा कहती हैं, "उन्हें अपना और ज्यादा ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन वे वही करते थे, जो उनका दिल कहता था." धर्मेंद्र कहते हैं, "उनके सगे-संबंधियों को उन्हें अपनी सेहत का इस तरह सत्यानाश नहीं करने देना चाहिए था." सब उन्हें पीना कम करने की सलाह देते रहे. पृथ्वीराज कपूर के 76 वर्षीय भाई त्रिलोक कपूर बताते हैं, "वह कोर्टिजोन मिश्रित

(ऊपर बाएं से) रणधीर, ऋषि, राजीव; और रीमा (बाएं) व रितु

विंटोलिन दवा लेता था. मैंने उसे मना किया था कि यह जल्दी आराम तो देती है मगर इसका तभी इस्तेमाल करो जब बेहद जरूरी हो."

लेकिन त्रिलोक कपूर बताते हैं कि राज उनकी बहुत इज्जत करते थे. उनके सामने न तो वे सिगरेट पीते थे, न ही शराब. जिन दिनों वे अपनी फिल्म के संपादन में व्यस्त होते, उन दिनों शराब की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखते थे.

राज कपूर के बच्चों ने बचपन में उनकी कमी जरूर महसूस की है. ऋषि कहते हैं, "अपनी फिल्मी दुनिया में ही वे चौबीसों घंटे व्यस्त रहते." रणधीर भी स्वीकार करते हैं, "हमें उनसे डर लगता था लेकिन जैसे-जैसे हम बड़े होते गए, हमारे संबंध दोस्ताना होते गए. हम लड़कियों के बारे में बातें करते और मजाक भी करते." लेकिन काम के प्रति उनका नजरिया विशुद्ध पेशेवर था. उनके सबसे छोटे बेटे 25 वर्षीय राजीव बताते हैं, "शूटिंग के दौरान वे हमें निर्देशन देने के बजाय इस तरह प्रेरित करते थे कि हम खुद ही काम कर सकें. दूसरे निर्देशक तो सिर्फ यह कहते हैं कि ऐसे करना चाहिए."

अपनी फिल्मों की कहानी, कलाकार, संगीत और संपादन में दिन-रात व्यस्त रहने के बावजूद वे अपनी निराशा या परेशानी कभी अपने बच्चों पर जाहिर नहीं होने देते थे. छुट्टियों में वे पुणे में अपने फार्म पर चले जाते थे या लंदन या स्विट्जरलैंड के इंटरलेकेन चले जाते थे. 'संगम' में उन्होंने यहीं के दृश्य फिल्माए. वे अक्सर कहा करते थे कि उनका सपना है कि 24 गायों और 12 ग्वालिनों सहित इंटरलेकेन में बस जाएं.

खाली वक्त में क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में जाकर एकाध सेट टेनिस या कभी-कभार रमी का लुत्फ उठाते थे. या फिर दीवाली की रात को जुआ खेलते. ऋषि कहते हैं कि उन्होंने एक बार कहा था कि फिल्में ही उनके जीवन का सबसे बड़ा जुआ है. जब भी उनके बच्चे किसी मुसीबत में होते, राज का सहारा उन्हें जरूर मिलता. लेकिन कुल मिलाकर वे एक आत्मलीन व्यक्ति ही थे. रणधीर बताते हैं, "वीडियो पर भी बस अपनी ही फिल्में देखा करते."

जब राजीव को 'एक जान हैं हम' में हीरो की भूमिका के लिए चुना गया तो हीरोइन के चयन पर सुझाव मांगने पिता के पास आए. राज बोले, "बेटा, अपनी समस्या से खुद निबटो, इसी से तुम काम याब आदमी बनोगे." आखिरी दिनों में बिलकुल एकाकी हो गए थे. उनके साथी बन गए थे—पक्षी, शराब और उनकी अपनी फिल्में.

—सलिल त्रिपा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

थे." और राज कपूर को भी आम पर अपने असर का अंदाज था. रूस में वाले भारत महोत्सव के लिए राज कपूर क फिल्म बनाने वाले सिद्धार्थ काक से ी कहा भी था, "मैं तो अनपढ़ हूं, ए मैं फुटपाथ के आदमी के साथ अपने काकार कर सकता हूं और उसके लिए म्य बन सकता हूं."

गों की जुबान पर किस तरह अपने गीत दिए जाएं, इसका गुर भी राज कपूर को था. उनके गीत आज हमारी चेतना के ंग बन गए हैं— चाहे वह 'आवारा' म भर जो इधर मुंह फेरे' हो या त' का 'जिया बेकरार है' या 'संगम' स्त दोस्त ना रहा' या 'बॉबी' का 'झूठ कौवा काटे' या फिर 'सत्यम शिवम ' का 'चंचल शीतल निर्मल कोमल'.

की फिल्मों में औरतों के चित्रण पर कुछ कहा जा चुका है. कोई उन्हें को बुरी नजर से निहारने वाला कहता है, तो किसी ने उन पर औरतों के शोषण का आरोप लगाया और किसी ने उन्हें आधुनिक कृष्ण बताया.

ऐसा लगता है कि जिस दिन नरगिस ने आर.के. स्टुडियो से कदम निकाला, उनकी फिल्मों में औरत का शोभनीय चित्रण भी बंद हो गया. उनके जाने के बाद पहली फिल्म बनी 'जिस देश में गंगा बहती है.' इसमें पद्मिनी झरने के नीचे नहाते हुए दोनों हाथों से पानी उड़ती हैं और गाती हैं. 'ओ मैंने प्यार किया' और फिर 25 बरस बाद राज कपूर ने मंदाकिनी पर 'राम तेरी गंगा मैली' में लगभग यही दृश्य फिल्माया. और विज्ञापन फिल्मों के निर्माताओं ने लिरिल साबुन के विज्ञापन में ऐसे ही दृश्य को खूब भुनाया. लेकिन भारतीय पुरुषों के मन को राज कपूर ने सबसे अच्छी तरह समझा. औरतों के प्रति उनकी 'कलात्मक' दृष्टि और आज 'नग्नता' वाले दृष्टिकोण का फर्क बुजुर्ग अभिनेत्री दीना पाठक बताती हैं. सिमी कहती हैं, "जिस तरह फूल को पानी की जरूरत होती है, उसी तरह उन्हें रोमांस की जरूरत थी."

'बरसात' में हीरो की आंखों में कामासक्त नजरों से देखने वाली या उसकी बाहों में झूल कर आर.के. स्टुडियो का प्रतीक चिन्ह (जिसे राज कपूर अर्धनारीश्वर का प्रतीक मानते थे) बनाने वाली नरगिस हों, या 'संगम' में मशकबीन बजाते हीरो से नाराज होकर तैरती हुई दूर जाती वैजयंतीमाला हों या 'बॉबी' के अल्हड़ सेक्स की प्रतीक बनीं डिंपल कपाड़िया हों या 'प्रेम रोग' में करुणा की पात्र पद्मिनी कोल्हापुरे हों, या 'राम तेरी गंगा मैली' की मासूम मंदाकिनी हों या 'सत्यम शिवम सुंदरम' में खजुराहो की नायिका को

(ऊपर बाएं से) शोक संतप्तों के साथ इंका नेता मुरली देवड़ा (दाएं); मंदाकिनी; (नीचे दाएं से) शम्मी के साथ वी. शांताराम; और डिंपल

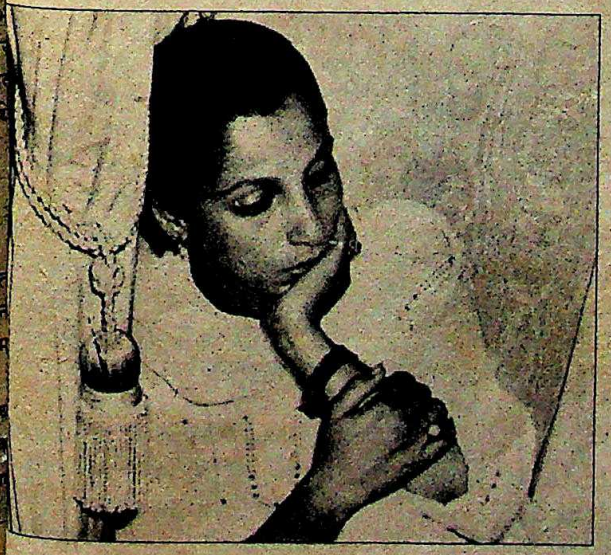

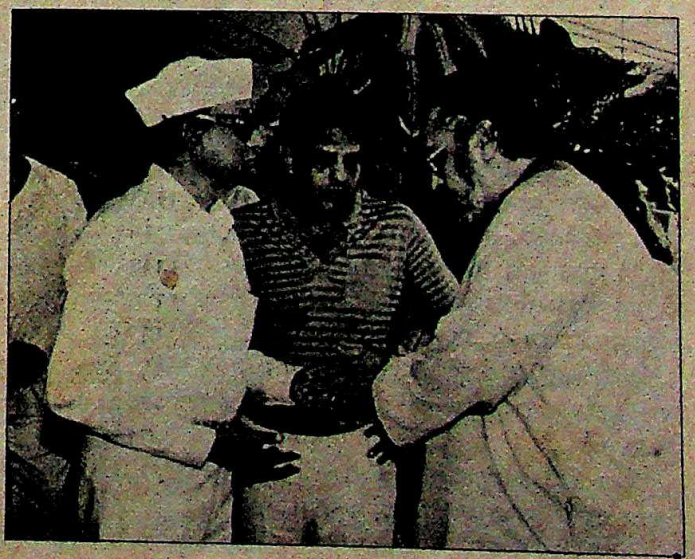

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जीवंत बनातीं जीनत अमान, राज कपूर ने इनमें से हरेक का व्यक्तिगत और विशिष्ट ख्याल रखा. उनसे बड़े स्नेह और लाड़ से काम लिया. इनमें से किसी ने भी राज कपूर पर 'औरत का शोषण' करने का आरोप नहीं लगाया. उन्होंने इन हीरोइनों को प्यार से छेड़ा, उनकी लल्लोचप्पो भी की, उनको चुटकुले सुनाकर हंसाया भी.

लेकिन इस मसखरेपन के पीछे एक तेज-तर्रार दिमाग भी था जिसने फिल्म को एक माध्यम के बतौर बहुत बारीकी से समझा था. उन्हें पता था कि वे कब निर्देशन कर रहे हैं और कब अभिनय. बासु भट्टाचार्य की फिल्म 'तीसरी कसम' में उनकी नायिका बनी वहीदा रहमान बताती हैं, "यह बासु भट्टाचार्य की पहली फिल्म थी और शैलेंद्र (फिल्म के निर्माता) राज कपूर के अच्छे दोस्त थे. लेकिन उन्होंने निर्देशक के काम में कभी भी दखल नहीं दिया." यह बात उनके अभिनय से भी जाहिर होती है. चोरी-चोरी, अंदाज, छलिया, अनाड़ी जैसी दूसरे निर्देशकों की उनकी फिल्में आज भी हाउसफुल जाती हैं.

काल्पनिक छवियों और ध्वनियों के बीच एक तथ्य उभरता है— आम आदमी की तरह राज कपूर भी वंचित है, सामाजिक परिस्थितियों का शिकार. उसे बहुत कुछ चाहिए भी नहीं. चाहिए तो बस ईमानदारी की रोटी, एक औरत का प्यार और एक ऐसा समाज जिसमें आपसी रिश्ते सहज हों. आज यह बडी सरल और बचकाना धारणा लगती है पर राज कपूर की असली उपलब्धि यह थी कि तमाम कठोर सचाइयों के बावजूद लोग उनकी सपनों की दुनिया में यकीन करते थे. उनकी ऐसी छवि बनाने में उनके साथियों की भूमिका छोटी नहीं थी. लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास और इंदरराज आनंद, पटकथा लेखक रामानंद सागर और वी.पी. साठे, संगीतकार शंकर जयकिशन, गीतकार हसरत जयपुरी और शैलेंद्र तथा उनकी आत्मा की आवाज मुकेश उनके साथियों में से थे.

उनका स्वर्णिम युग था वह. जब वे 'आजा रे अब मेरा दिल पुकारा' गाते थे तो लोग भी दर्द महसूस करते थे और जब वे 'हम तुमसे मुहब्बत करके सनम' गाते थे तो लोगों को लगता कि यह तो उनके ही दिल की आवाज है. और जब नरगिस प्यार का इकरार करतीं 'ये कौन जो दिल पर छाया, मेरा अंग-अंग मुस्काया' तो लोग खुश हो जाते. जब लक्ष्मण झूले पर से उन्होंने गाया 'हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है' तो लोगों को अपने देश पर नाज होने लगा. जब नरगिस ने अपनी मटकी नीची करके उन्हें पानी पिलाया और सवेरे-सवेरें गाया 'जागो मोहन प्यारे' तो लोगों के मन में भी विशुद्ध प्रेम की ललक जाग उठी. आवारा का सपने वाला दृश्य तो प्रेम की पराकाष्ठा ही थी.

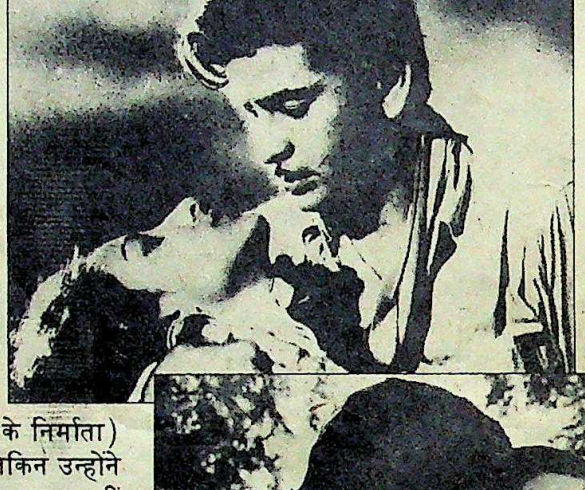

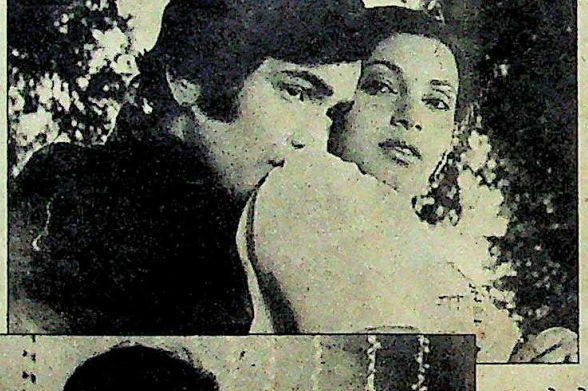

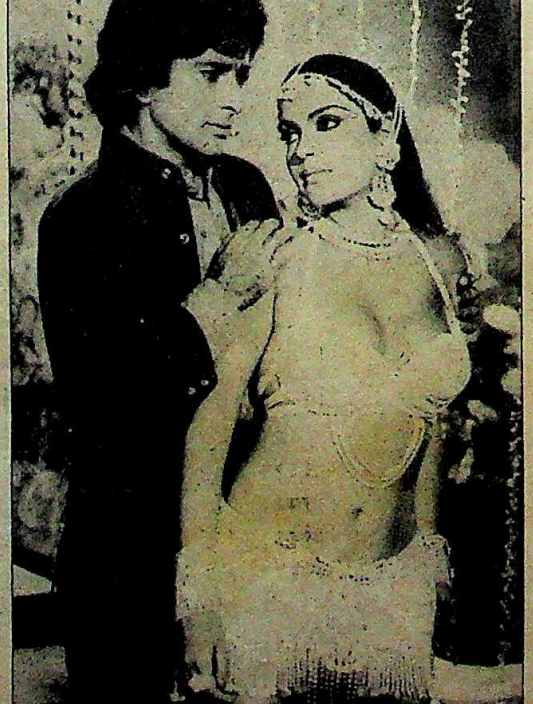

(ऊपर से) बरसात में नरगिस के साथ राज; तथा बॉबी और सत्यम शिवम सुंदरम के दृश्य

हिंदू परंपराओं से राज कपूर का लगाव गहरा था. आर.के. प्रोडक्शंस की हर फिल्म के शुरू में हम पृथ्वीराज कपूर को पूजा करते हुए देखते हैं और उनकी फिल्मों में भी हिंदू प्रतीक भरे हुए थे. अपने काम में राज कपूर एक संपूर्णतावादी थे. 'मेरा नाम जोकर' के गीत 'तीतर के दो आगे तीतर' के फिल्मांकन में खास दृश्य के लिए राजकपूर ने 14 दिन इंतजार किया था. 'मेरा जूता है जापानी' गीत को फिल्माने के लिए मन मुताबिक बादल दिखें, इसके लिए वे पूरी यूनिट को ऊटी ले गए थे.

उनकी पुरानी फिल्मों से उनकी नई फिल्मों की तुलना करना ठीक नहीं होगा. हर फिल्म अपने समय के अनुसार बनी थी. खालिद मोहम्मद कहते हैं, "उन्होंने 50 के दशक में जो कुछ किया, वही 80 के दशक में करते, यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए. व्यावसायिक दायरे में ही उन्होंने क्या उपलब्धियां हासिल कीं, हमें यह देखना चाहिए."

राज कपूर वीडियो और ऑडियो रिकार्डिंग की तकनीक के माध्यम से हमारे साथ बने रहेंगे. आर.के. स्टुडियो, इडली खाने की उनकी प्रिय जगह गीता भवन, बंबई के व्यावसायिक जगत के केंद्र में स्थित 'मरोसा' या चिकन पेटिस की उनकी प्रिय जगह फलोरा फाउंटेन को उनकी कमी जरूर अखरेगी. चेंबूर के गणपति जुलूस की अगली पंक्ति में भी उनकी गैर मौजूदगी खलेगी. और हर होली में आर.के. स्टुडियो के रंग के तालाब में सबकी डुबकी लगवाने के लिए भी अब वे नहीं होंगे. लेकिन हमारे दिलों में वे जरूर रहेंगे. 'राम तेरी गंगा मैली' की सफलता पर जयपुर में हुए एक समारोह में उन्होंने गाया भी था, 'हम ना रहेंगे, तुम ना रहोगे, फिर भी रहेंगी निशानियां.'

—सलिल त्रिपाठी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अमीर खुसरो

समन्वयवाद का सबक

अतीत की गलत धारणाओं को दूर करने का प्रयास

विघटन की ओर अग्रसर समाज को शायद अतीत का महान दिग्दर्शक ई राह दिखा सके. वृत्तचित्र निर्माता जबंस खन्ना ने इसी प्रेरणा से 16 खंडों के वी सीरियल 'अमीर खुसरो' के निर्माण बीड़ा उठाया था.

अपूर्व परिस्थितियों में जिए अमीर रो अपने समय के असाधारण व्यक्ति थे. 1253 में गंगा के किनारे एक कुलीन पिता और भारतीय मां के घर जन्म वाले खुसरो छोटी उम्र में ही सूफी संत रत निजामुद्दीन औलिया के पैरोकार बन . वे उस जमाने में हुए जब लों के आने से कुछ ही समय ले भारत अनिश्चितता के दौर से र रहा था. खुसरो के 72 वर्ष के वन में दिल्ली सल्तनत पर नौ शाहों की हुकूमत रही जिनमें से न के दरबार में वे भी रहे.

खुसरो कई इल्मों के माहिर रहे. यरी, भाषा विज्ञान, इतिहास र संगीत में नाम कमाने के पावा उन्होंने भारत के विभिन्न ों में हुए अनेक सैन्य अभियानों भी भाग लिया. लेकिन खुसरो ख्याति बतौर शायर ही ज्यादा यहां तक कि उनके निधन के सौ साल बाद भी गालिब ने ा: गालिब मेरे कलाम में क्यूं मजा न हो/पीता हूं धोकर रो-ए-शीरीं के पांव में.

फारसी में करीब चार लाख त्त (जिनमें अब लगभग एक ाई ही बचे हैं) लिखने के अलावा ो पहले बड़े कवि थे जिन्होंने खड़ी ी (अथवा हिंदवी) और ब्रज भाषा को ैत्यिक दर्जे तक ला खड़ा किया. उन्होंने लोगों की इन भाषाओं में अनेक ाएं कीं और इस मान्यता को झूठा त कर दिया कि साहित्य रचना सिर्फ सी भाषा में ही संभव है.

न्ना का टीवी सीरियल अमीर खुसरो जिंदगी के इसी पहलू पर केंद्रित है. र की जिंदगी का सीधा-सादा ऐतिक चित्र खींचने के बजाय खन्ना ने, जिनकी इस जनवरी में सीरियल पूरा होने के तुरंत बाद मृत्यु हो गई थी, सांप्रदायिक स्थिति के प्रति खुद अपनी चिंता जताने के लिए एक विशेष सिनेमाई युक्ति का प्रयोग किया है. कहानी के बीच कहानी जोड़कर और कभी अतीत, कभी वर्तमान में ले जाकर उन्होंने उपमहाद्वीप में हिंदू-मुस्लिम संबंधों के इतिहास को विकृत करने वाली अस्पष्टताओं को दूर किया है. इस प्रक्रिया में खुसरो के जीवन और व्यक्तित्व से संबंधित तथ्य गड्डमड्ड हो गए हैं. कुल मिलाकर सीरियल एक ऐसा भावुक दस्तावेज बन गया है जो दो महान सभ्यताओं और धर्मों के मेलमिलाप का दौर लौटा लाने का संदेश देता है.

"इतिहास ठीक से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सांप्रदायिकता खत्म हो"
राजबंस खन्ना

खुसरो की भूमिका में रैना

केन्स में महात्मा बुद्ध पर बनाए अपने पहले वृत्तचित्र पर पुरस्कार पाने वाले खन्ना ने अपनी मृत्यु से पहले लिखा था, "मैं अमीर खुसरो पर महज एक सीरियल नहीं बना रहा. दरअसल मैं बच्चों को समझाना चाह रहा हूं कि अंग्रेजों के जमाने से पढ़ाया जा रहा इतिहास उसका विकृत रूप है. इसे ठीक से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि लोगों के दिमाग में भरा सांप्रदायिक जहर दूर किया जा सके." ये फिल्मकार खुद अपनी जिंदगी में सांप्रदायिकता के भुक्तभोगी रहे हैं और उन्होंने इसके खिलाफ लड़ाई भी लड़ी है. विभाजन के दौरान लाहौर से भागकर उन्होंने आक्रमणकारियों के खिलाफ शेख अब्दुल्ला की कश्मीर मिलिशिया की अगुआई की. पंडित नेहरू की धर्मनिरपेक्ष राजनीति के भी वे कट्टर समर्थक थे.

क्या आप जानते हैं कि शिवाजी दरगाहों और मंदिरों दोनों में जाते थे और बाबा याकूब उनके पीरों में से थे; उनका विश्वसनीय नौसेनापति एक मुसलमान था और अफजल खां के विरुद्ध उनका सहयोगी सिद्दी इब्राहिम था; औरंगजेब का सिपहसालार राजा जय सिंह था; तथा राजा मान सिंह ने राणा प्रताप के खिलाफ अकबर की फौजों की अगुआई की? इतिहास के ये उदाहरण बताते हैं कि मध्य युग में युद्धों की वजह मजहब नहीं थे बल्कि ये लड़ाइयां सत्ता की खातिर की गईं—यह किस्सा एक मुसलमान फकीर उन बच्चों को सुनाता है जो सांप्रदायिक दंगों के कारण दिल्ली के एक खंडहर में फंस जाते हैं. आज के जमाने की इस घटना को अमीर खुसरो की जिंदगी और कामों से जोड़ा गया है.

अमीर खुसरो के समन्वयवादी नजरिये पर सूफी दर्शन की गहरी छाप रही है. सूफी और भक्ति आंदोलनों ने हिंदू-मुसलमानों के मेलमिलाप को एक नया आयाम दिया था. खुसरो की शायरी में यही संदेश छिपा है कि आक्रमणकारियों ने इस देश की सभ्यता को आत्मसात कर लिया था. अजीम शायर पर बने इस सीरियल के माध्यम से खन्ना चेताते हैं कि अगर समय रहते इतिहास से कोई सबक नहीं सीखा गया तो सांप्रदायिकता जन्नत जैसे हमारे देश को उजाड़ देगी.

—एम. रहमान

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कोचिंग केंद्र

धड़ल्ले से चलता धंधा

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जबरदस्त मारामारी

मानो एकाएक उनकी धूम मच गई हो. नुक्कड़ों पर ताजा पुती दीवारों और सार्वजनिक बसों की पुश्त पर, स्थानीय और राष्ट्रीय दैनिकों में प्रमुखता से छपे विज्ञापनों में तथा यहां तक कि सड़कों के किनारे खड़े पेड़ों के ऊपर लटकाए गए विज्ञापन पटों में भी हर कहीं उनकी ही चर्चा है. भारत के हर शहर में इन दिनों कोचिंग केंद्र उग आए हैं और धड़ल्ले से अपना धंधा चला रहे हैं.

अकेले कलकत्ता में ही ऐसे 250 से अधिक केंद्र हैं. पटना में करीब 50 कोचिंग केंद्रों में हर साल लगभग 5,000 छात्र दाखिला लेते हैं. लखनऊ में ऐसे संस्थानों की संख्या 40 तक पहुंच गई है. इन केंद्रों में अलग-अलग पाठ्य क्रमों के लिए 300 से लेकर 12,500 रु. तक फीस ऐंठी जाती है. कुछ केंद्र तो 100 रु. प्रति घंटा के हिसाब से भी फीस लेते हैं. इनमें सरकारी सेवा, प्रबंधन और आईआईटी की प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर बैंकों की क्लर्क ग्रेड परीक्षाओं और नेशनल डिफेंस अकादमी की प्रवेश परीक्षाओं तक की कोचिंग दी जाती है. छात्रों की बड़ी संख्या इन कोचिंग केंद्रों की ओर उमड़ पड़ी है.

प्रवेश पाने के लिए भारी मारामारी के बल पर ही ये कोचिंग केंद्र फल-फूल रहे हैं. पिछले साल पांच आईआईटी संस्थानों में 1,500 स्थानों के लिए 70,544 उम्मीदवार उनकी संयुक्त प्रवेश परीक्षाओं में बैठे थे. लोक सेवाओं के लिए ही 1986 की परीक्षाओं में बैठे 1.63 लाख उम्मीदवारों में से मात्र 855 चुने गए. बैंकिंग सेवा के लिए भी प्रार्थियों की भीड़ वैसी ही है. दिल्ली और हरियाणा में बैंक क्लर्कों की 1,700 विज्ञापित रिक्तियों के लिए करीब 1.63 लाख लोगों ने आवेदन किया, चुने गए सिर्फ 500 ही. और इस साल देश भर के बैंकों में 35 प्रोबेशनरी अफसरों के पद के लिए 46,595 उम्मीदवार मैदान में हैं.

कड़ी प्रतियोगिता के इस वातावरण का ज्यादा-से-ज्यादा लाभ उठाने के लिए ही कोचिंग केंद्र उग आए हैं. वे मनमानी फीस बटोरकर खूब चांदी काट रहे हैं. नए कोचिंग कॉलेज जहां कंप्यूटर क्लब और वातानुकूलित कक्षाओं जैसी बढ़िया सुविधाएं दे रहे हैं, वहीं पुराने कॉलेज इस भीड़ भरे बाजार में अपना अस्तित्व बनाए रखने की जीतोड़ कोशिश में लगे हुए हैं. खर्चे कम करने के लिए वे लाइब्रेरी जैसी सुविधाओं को भी दरकिनार कर रहे हैं. आम तौर पर मालिक-प्रिंसिपल खुद ही दर्जन भर प्रमुख पत्रिकाओं में से छात्रों के लिए ताजा समाचारों की एक फेहरिस्त छांट लेते हैं. ऐसे अधिकांश मालिकों के घर में ही चलते हैं और उ पत्नियां सेक्रेटरी का काम संभालती हैं. ने तो सड़क के किनारे ही पटरी दुका मिलते-जुलते अपने दफ्तर बना रखे हैं. नियुक्त शिक्षक इसे पूरे वक्त की शायद ही मानते हैं. ज्यादातर तो पढ़ कोई रुचि नहीं लेते. इनमें से कुछ बेरो ग्रेजुएट या अवकाशप्राप्त लोग होते हैं.

इनमें सबसे अधिक सफल 'ब्रिलिएं टोरियल्स' नामक केंद्र है. इसमें कई त कोर्स पढ़ाए जाते हैं. इसने 9वीं कक्षा से छात्रों के लिए एकमुश्त कार्यक्रम बना जिसके तहत वह उन्हें चार साल के किसी एक आईआईटी में निश्चित रू दाखिला दिलाने का आश्वासन देता है. छात्रों में 'ब्रिलिएंट' में दाखिला लेने की सनक सवार है. मद्रास स्थित इस कोचिं में अकेले आईआईटी में दाखिले की तैया लिए ही हर साल 10,000 से 15,00 छात्र भरती होते हैं. 'ब्रिलिएंट' के संस्थ एन. थानू का कहना है कि 19 पत्राचार कोचिंग शुरू करने के उनका कारोबार भयानक रूप से लगा. और केंद्र उन्नति करने लग

दरअसल स्कूल-कॉलेजों की स्था में खामियों की वजह से ही की ये दुकानें फली-फूली हैं. प्री-मे परीक्षा की तैयार कर रहे लखन एक बीएससी छात्र अनुराग शर्मा हैं, "इन कोचिंग केंद्रों में प्रति परीक्षा की तैयारी कर रहे लखन जाते हैं जो स्कूल-कॉलेजों में सिखाए जाते." राजधानी के पब्लिक कॉलेज ऑफ कांपिटिश मालिक लेफ्टिनेंट कर्नल आई मनचंदा मानते हैं कि "हमारी त

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

की सभी दुकानें समाज पर कलंक हैं'' नका यह भी कहना है कि ''ये दुकानें शिक्षा व्यवस्था की ही उपज हैं.''

चिंग केंद्र छात्रों में इसलिए भी लोकप्रिय हुए हैं क्योंकि वे पूरी संदर्भ को संक्षेप में मुहैया करते हैं. एस.के. ा का बेटा तरुण 'ब्रिलिएंट ट्यूटो- ' और 'अग्रवाल क्लासेज़' से दो साल लेने के बाद इस साल अप्रैल में ईटी की संयुक्त प्रवेश परीक्षा में बैठा. ोचिंग केंद्रों के बारे में भाटिया का ण नितांत व्यावहारिक है. उनका है, ''ये कक्षाएं न हों तो छात्रों को मेहनत करनी पड़े. ये केंद्र सैकड़ों ं से नोट तैयार करके छात्रों को कराते हैं. छात्रों के सामने हर विषय ना विविध और विस्तृत रूप ये केंद्र वैसा तो अच्छे-से-अच्छे स्कूल में भी नहीं होगा.''

की बात में दम भी है. कोचिंग केंद्र को लेक्चर नोट तो मुहैया ी हैं, उन्हें समूह चर्चा, लेक्चर क्टिस टेस्ट के जरिये भी प्रशि- ते हैं. मौखिक परीक्षाओं में न के लिए ये मनोवैज्ञानिक भी आयोजित करते हैं. 'एक मेडिकल कॉलेज' के दाखिले की गाए और हाईस्कूल में उम्दा ाने वाले 17 वर्षीय जिगनेश हते हैं, ''मैं खुद काफी मेहनत ता हूं. पर कोचिंग कॉलेज में यह एहसास बना रहता है कि खाई जारी है.''

शायद राव के 'आईएएस कल' की सफलता का भी यही राज है. दिल्ली में इसे एक प्रतिष्ठित संस्थान माना जाता है. आंध्र विश्वविद्यालय से डॉक्टर की मानद उपाधि पाए डॉ. राव कहते हैं, ''मैं खुद कभी आईएएस की परीक्षा में नहीं बैठा लेकिन मैं छात्रों को इसमें बैठने का गुर सिखाता हूं. ऐसी कला आजकल स्कूलों में नहीं सिखाई जाती.'' इस कला को सीखने के लिए राव के केंद्र में आईएएस कोचिंग के पूरे कोर्स पर 12,475 रुपए खर्च आता है.

बंबई में सफल उम्मीदवारों की कोचिंग के लिए 'अग्रवाल क्लासेज़' मशहूर हैं. 1100 रु. में इसका दस माह का आईआईटी प्रवेश परीक्षा पत्राचार कोर्स काफी लोकप्रिय है. हर साल प्रायः 6,000 छात्र इसमें भर्ती होते हैं.

राव के स्टडी सर्किल जैसी संस्थाएं जहां समाज के ऊपरी वर्ग की जरूरतें पूरा करती हैं, वहीं कोचिंग केंद्र, स्टडी सर्किल और ट्यूटर्स ब्यूरो जैसी संस्थाएं प्रायः हर इलाके में उग आई हैं. कलकत्ता के एक रिहाइशी इलाके में मोटे तौर पर किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला है कि करीब 70 फीसदी छात्र या तो निजी शिक्षक रख लेते हैं या किसी कोचिंग केंद्र में दाखिला लेते हैं. दिल्ली में 'ब्रिलिएंट' से पत्राचार कोर्स कर रहे बारहवीं कक्षा के छात्र नवीन तनेजा कहते हैं, ''हमारी विज्ञान कक्षा के करीब सभी 200 छात्र कहीं-न-कहीं कोचिंग लेते हैं.''

दरअसल ये कोचिंग संस्थाएं असुरक्षा की इसी भावना को भुना रही हैं. वे उम्मीदवारों को अपने प्रतिद्वंद्वियों पर भारी पड़ने का वायदा और कड़ी प्रतियोगिता की दुनिया के सभी महत्वपूर्ण पदों को दिलाने का आश्वासन देकर फांसती हैं. इस तरह कॉलेजों और स्टडी सर्किलों की यह नई पौध अब शिक्षा व्यवस्था का अभिन्न अंग बन चुकी है. ज्यादातर अभिभावकों के बजट में बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के खर्च का एक बड़ा हिस्सा अब इन कोचिंग केंद्रों के लिए होता है. भाटिया कहते हैं, ''अगर किसी अभिभावक को अपने बच्चे के कैरियर के प्रति रुचि है तो उसे अतिरिक्त कोचिंग पर पैसा लुटाना ही पड़ता है.''

दिल्ली के 'प्राइवेट ट्यूटर्स ब्यूरो' के संस्थापक के.जे. लाल बताते हैं, ''हमारी सेवाएं डॉक्टरों या वकीलों जैसी हैं. जैसे वे विशेषज्ञ और पेशेवर हैं, वैसे हम.'' लाल के ब्यूरो में दो साल पहले 600 छात्र ही थे. अब यह संख्या बढ़कर 1,000 तक पहुंच गई है. लाल मानते हैं कि ज्यादातर संपन्न अभिभावक ही उनके ब्यूरो में आते हैं और एक केंद्रीय मंत्री भी उनके ग्राहक हैं.

पर कोचिंग केंद्र मात्र इतनी सफलता से ही संतुष्ट नहीं हैं. इनमें से ज्यादातर मुनाफा बढ़ाने और प्रतिस्पर्धा से निबटने के लिए लगातार बेहतर दांवपेंच अपनाने में लगे हुए हैं. मसलन दिल्ली का एस.एन. दासगुप्ता कॉलेज आईएएस कोचिंग का पूरा कोर्स करने वाले छात्रों को 15 फीसदी छूट देता है. राव के स्टडी सर्किल में भी ऐसी छूटें हैं. 'ब्रिलिएंट' सर्वोच्च स्थान पाने वाले अपने छात्रों को तीन लाख रु. के नकद पुरस्कार देता है.

कलकत्ता के ट्यूशन पढ़ाने वाले आलोक राय इस प्रवृत्ति पर खेद प्रकट करते हैं, ''इससे शिक्षा एक बाजारू चीज बन गई है. ऐसी दुकानें शिक्षा को दूसरे सामान की तरह पैकेट में बंद करके बेच रही हैं.'' जब तक देश की शिक्षा व्यवस्था में भारी खामियां रहेंगी, ये कोचिंग केंद्र फलते-फूलते रहेंगे.

—नंदिता सरदाना और ब्यूरो रिपोर्ट

कार्टूनः अजीत नैनन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

परीक्षाएं

अंकों के लिए होड़

बेहतर नतीजे के लिए तनाव

वो भी क्या दिन थे. 'स्कूल से अलविदा' लेते ही आजादी का एहसास गहरा उठता और अल्हड़पन का खुशनुमा अंत जिंदगी को तमाम रंगीनियों से भर देता. बच्चों के लिए हालात शायद अभी वैसे ही हों लेकिन स्कूल नोटिस बोर्डों पर चिपके नतीजों को देखने आए तनावग्रस्त चेहरों पर ऐसी झलक नहीं मिलती. पिछले पूरे महीने भर देश के अनेक सेकेंडरी शिक्षा बोर्डों ने सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं के नतीजे घोषित किए. बहुतों के लिए तो ये नतीजे मानो तनाव भरे आगामी कुछ महीनों की शुरुआत थी.

ज्यादा परेशान तो अभिभावक थे. दिल्ली के एक इंजीनियरिंग सलाहकार आर.के. सरदाना का चेहरा खिन्नता से भर उठा था. रामजस पब्लिक स्कूल का छात्र रहा उनका 17 वर्षीय बेटा, भारत, विज्ञान के विषयों में 80 फीसदी अंक ही ले पाया. बधाई देने पर वे भड़क उठे, "किस बात की बधाई? 80 और 60 में फर्क ही क्या है. अगर उसे दाखिला नहीं मिला तो क्या फायदा?" इंजीनियरिंग कॉलेजों अथवा कला, वाणिज्य या विज्ञान के कोर्सों में दाखिला वास्तव में बड़ी समस्या है. हल बस एक ही है कि छात्र के अंक 90 फीसदी से कम न हों.

उच्च अंक पाने वाले छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. गणित में 90 फीसदी अंक कोई मायने नहीं रखते. हजारों छात्र इतने अंक पा लेते हैं. 99 अथवा कम-से-कम 98 अंक ही अच्छे माने जाते हैं. और अंग्रेजी जैसे विषय में भी देश भर के पैमाने पर अधिकतम अंक 89 फीसदी रहे.

इसकी एक वजह तो शायद प्रश्नपत्रों की शैली है. विज्ञान विषयों में 82 फीसदी अंक पाने वाले दिल्ली पब्लिक स्कूल के तन्मय जायसवाल का कहना है, "आजकल वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे जाते हैं. इसमें ज्यादा अंक मिलने की संभावना रहती है." यह कदम परीक्षकों के पक्षपात और 'अवैज्ञानिक तरीके से अंक दिए जाने' की आलोचना के बाद उठाया गया था.

उच्च अंकों की एक अहम वजह ऐसे स्कूलों की संख्या में बढ़ोतरी होना भी है जो छात्रों की अच्छी तरह तैयारी कराते हैं. एक दशक पहले तक भी योग्यता सूची में कुछ गिने-चुने प्रतिष्ठित स्कूलों का ही बोलबाला हुआ करता था. पर आज केंद्रीय सेकेंडरी शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष एच.एस. सिंघा मानते हैं कि "विषयवार सर्वोच्च स्थान पाने वाले छात्र अब अनेक स्कूलों से आने लगे हैं."

शिक्षा नीति का उद्देश्य तीव्र प्रतियोगिता को निरुत्साहित करना है. इसलिए बहुत से शिक्षा बोर्डों ने योग्यता सूची बनाना ही बंद कर दिया है. अब केवल एक विषय में सर्वोच्च स्थान पाने वाले छात्रों के नाम ही घोषित किए जाते हैं. लेकिन नई नीति ज्यादातर उन नए स्कूलों में ही जोर पकड़ती दिखती है जिन्होंने सर्वोच्च स्थान पाने वाले छात्रों की संख्या बढ़ाने में योगदान दिया है. नतीजा यह है कि सर्वोच्च स्थान पाने वाले कुछ छात्रों पर अपनी प्रतिष्ठा और आशा केंद्रित करने के बजाय वे 'चहुंमुखी परिणाम' पर ध्यान देने लगे हैं. सरदार पटेल स्कूल की 47 वर्षीया प्रिंसिपल विभा पार्थसारथी कहती हैं, "हमारे स्कूल में कोई भी सर्वोच्च स्थान पाने वाला छात्र नहीं हुआ है. फिर भी हम बेहद खुश हैं."

इसी तरह, दिल्ली के पंजाबी बाग में हंसराज मॉडल स्कूल के 58 वर्षीय प्रिंसिपल तिलकराज गुप्ता अपने स्कूल के सर्वोच्च स्थान पाने वाले छात्रों का ही जिक्र नहीं करते, वे परीक्षाओं को 'हमारी शिक्षा प्रणाली के लिए हानिकारक' मानते हैं. लेकिन ऐसे स्कूलों ने सर्वोच्च स्थान पाने को तरजीह देने का काम जहां छोड़ दिया है, वहीं उनके प्रिंसिपल अपेक्षा करते हैं कि छात्र अच्छे अंक पाएं. गुप्ता कहते हैं, "प्रतियोगिता में तो उन्हें उतरना ही पड़ेगा."

शिक्षक चाहे इस बात पर जोर न भी दें पर माता-पिता और खुद छात्र ऐसा करते हैं. ज्यादातर बच्चे, खासकर मध्यमवर्ग के व्यवसायियों के बच्चे, स्कूल के अंतिम व की परीक्षा से बहुत पहले अपनी योजना बना लेते हैं. डॉक्टरी, इंजीनियरिंग औ आईएएस सरीखे पेशे छात्रों को ज्या आकर्षित करते हैं. पर बहुतों के पास इ पसंद की कोई ठोस वजह नहीं होत एक छात्र का कहना है कि उसका ल आईएएस करने का है पर वह इंजीनियरि पढ़ना पसंद करेगा क्योंकि "इंजीनियरिंग ही पता चलता है कि आप प्रतिभाशाली या नहीं." विभा पार्थसारथी कहती हैं माता-पिता के दबाव के कारण ही ज्यादा छात्र ऐसा करते हैं.

स्कूल पास कर लेने वाले छात्रों का ए

कार्टून: बजील

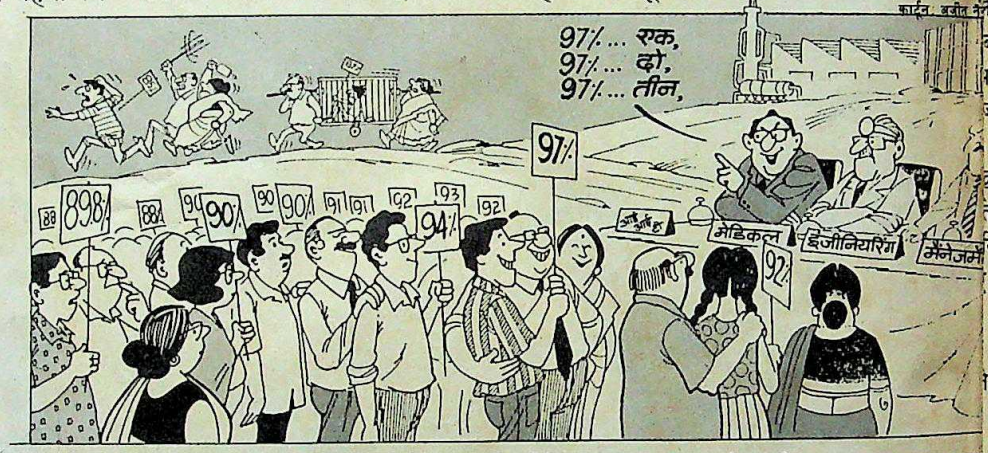

दूसरा ख्वाब है परदेस जाकर बसना. भा योजनाओं के बारे में बातचीत के दौर कुछ स्कूली छात्रों ने बताया कि वे वैमानि इंजीनियरिंग के प्रति उत्सुक नहीं हैं का यह कि अमेरिका में जरूरत से कहीं ज्या वैमानिक इंजीनियर हैं और अगर उन्ह भी यही व्यवसाय अपनाया तो उन्हें अ रिका में जगह नहीं मिलेगी.

जाहिर है, शिक्षा के योजनाकारों सोच और छात्रों की प्राथमिकताओं के ब एक गहरी खाई है. मसलन, एक दशक पह जब 10 + 2 पद्धति लागू की गई तो उस विवादास्पद पहलू था 10वीं कक्षा के ब की शिक्षा को उच्च अध्ययन और व्य सायिक धाराओं में बांटना. इस साल केंद्री बोर्ड की परीक्षा में बैठे 53,456 छात्रों से मात्र 275 ही व्यावसायिक धारा संबद्ध थे. इसकी एक वजह आधारभूत का अभाव होना है. लेकिन इससे भी ज्य महत्वपूर्ण कारण यह है कि जो लोग मैकेनिक या बढ़ई बनना चाहते हैं, वे स्कूल के प्रमाणपत्र की जरूरत महसूस नहीं क इस बीच उच्च शिक्षा की आकांक्षा रा वालों के लिए अंकों की यह बेतहाशा तनाव और परेशानियों का सबब बन गई

—डेविड देव

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दू मठ

समाधि से समाज सेवा तक

क्षिण भारत के मठों का नारा मानवतावाद और समाज सेवा

ढ़िवाद और धार्मिक कट्टरता के प्रतीक रहे दक्षिण भारत के हिंदू मठों अब सैद्धांतिक बदलाव की हवा चलने ी है. इस महत्वपूर्ण तब्दीली के अगुआ के मठाधीश ही हैं जिनमें से अधिकांश धिता के खोल से निकलकर नई गति-ता की ओर अग्रसर हैं.

बदलाव के ये संकेत सर्वत्र दिखते ौर इनकी विविधता भी हैरत-ज है. मसलन:

दक्षिण भारत के हिंदू मठों द्वार जो हाल तक अनुसूचित तयों और जनजातियों के लोगों लिए बंद थे, अब हरिजनों के खुल गए हैं.

ज्यादातर मठों ने हरिजनों गरीबों में सामाजिक कार्य के लिए व्यापक अभियान छेड़ हैं.

मठों के द्वार अब विधवाओं के भी खुलते जा रहे हैं. पहले क तौर पर कलंकित जाने के कारण प्रवेश वहां वर्जित जाता था.

मठाधीशों के लिए मानी जाने वाली ओं पर बंधन भी अब ए हैं. वे विमानों पर देश-विदेश की एं करते हैं और इस उन प्राचीन हिंदू ग्रंथों नदेखी करने लगे हैं संन्यासियों के लिए प्रकार के वाहन के ल की मनाही है.

कांची मठ तो शुरू से ही ब्राह्मणों का ना जाता रहा है. लेकिन अब वहां के श स्वामी जयेंद्र सरस्वती के साथ र नाडर और गौंडर जातियों के ह्मण ही दिखने लगे हैं.

सबसे यही संकेत मिलता है कि 20 ी के स्वामियों का जमाना आ गया है. श लोग अब एकांत में बैठकर वेदपाठ माधि में लीन नहीं रहते. वे भारतीय समाज में गरीब और परित्यक्त लोगों को ऊंचा उठाने के अपने उपदेशों पर अमल करने के लिए आगे आने लगे हैं.

सबसे स्पष्ट बदलाव तो तमिलनाडु में चिंगलपुट जिले के कांचीपुरम स्थित शंकराचार्य मठ में दिखता है. अब तक 'केवल ब्राह्मणों के लिए' आरक्षित रहे इस मठ ने अपने द्वार सभी के लिए खोल दिए हैं. करीब 25 वर्ष से कांची मठ के प्रमुख बने चले आ रहे 55 वर्षीय जयेंद्र सरस्वती ने दरअसल कुछ कार्यक्रम तो विशेष रूप से हरिजनों के लिए शुरू किए हैं. फरवरी में उन्होंने कांचीपुरम और चिंगलपुट में हरिजनों के पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों को चाक, अगरबत्ती और फिनोल आदि बनाने की दस्तकारी सिखाने के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र खोला.

पिछले पखवाड़े मठ के जनकल्याण आंदोलन के तहत दक्षिणी मद्रास में 45 हरिजन छात्रों के लिए 15 दिन का नैतिक प्रशिक्षण कोर्स पूरा हुआ. इसके अलावा लड़कों को रेडियो और टीवी की मरम्मत और लड़कियों को सिलाई के लिए तीन-तीन महीने का प्रशिक्षण देने की भी योजना है. इसमें प्रवेश सभी जातियों के लिए खुला है. दक्षिण भारत में इस सामाजिक क्रांति के सूत्रधार स्वामी कहते हैं, "मैं ओडीसा में बरहामपुर और मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर की जनजातियों और बिहार में रांची के आदिवासियों के लिए भी व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना चाहता हूं."

उदारवाद की यह लहर दूसरे मठों में भी नजर आती है. कर्नाटक में मंगलूर के नजदीक उडिपी के बेहद रूढ़िवादी अडमार मठ के 60 वर्षीय स्वामी विभुदेश तीर्थ स्वामीजी अब हरिजनों में सामाजिक कार्य कर रहे हैं. यह आठ माधव मठों में से एक है जिसे उडिपी में स्थापित हुए 800 साल से भी अधिक हो गए हैं. स्वामीजी ने हरिजनों के लिए चिकमंगलूर जिले के संगमेश्वर गांव में 100 से भी अधिक और बंगलूर के निकट भैरथी बेंडे गांव में 52 मकानों के निर्माण के लिए न सिर्फ पैसा दिया बल्कि सारा काम भी उन्हीं की देखरेख में हुआ. पिछले पखवाड़े तो उन्होंने सुधार के लिए कोलार जिले के दो गांवों को भी चुना है.

काफी पढ़े-लिखे पर सीधे-साधे स्वामीजी हरिजनों में काम करने की खातिर भैरथी बेंडे गांव में ही रहते हैं. गांव के 23 वर्षीय कॉलेज छात्र वी. कृष्णप्पा कहते हैं, "कर्नाटक में स्वामीजी हरिजनों के बीच रह रहे शायद पहले ब्राह्मण हैं. हमारे लिए बैल और बैलगाड़ियां खरीदकर उन्होंने हमें एक नई जिंदगी दी है."

सभी फोटो: श्याम टेकवानी

भैरथी बेंडे गांव में हरिजनों के संग विभुदेश तीर्थ स्वामीजी: नई लहर

अधिकांश हिंदू मठाधीश अब धर्मांधता के अपने पुराने खोल से निकलकर नई प्रकार की गतिशीलता की ओर अग्रसर होने लगे हैं

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विभुदेश तीर्थ स्वामीजी ने हरिजनों को पूजा से पहले अपने चरण दूध से धोने की अनुमति देकर उनकी पद-पूजा भी स्वीकार कर ली है. वे बताते हैं, "पहले हिंदू मठ उसी जाति के धार्मिक अनुष्ठान करवाया करते थे जिस जाति का स्वयं मठाधीश होता था. लेकिन अब मठ हर समुदाय और जाति के लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान करता है."

रूढ़िवादी हिंदू मठों ने अपने द्वार न सिर्फ हिंदू धर्म की सभी जातियों और समुदायों बल्कि दूसरे धर्म के लोगों के लिए भी खोल दिए हैं. स्वामी जयेंद्र सरस्वती के अनन्य

स्वामी जयेंद्र सरस्वती: सामाजिक क्रांति के अगुआ

भक्तों में एक मुसलमान भी है. पिछले पखवाड़े कर्नाटक में शृंगेरी के शंकराचार्य मठ में आए श्रद्धालुओं में तीन ननें भी थीं. चार वर्ष पहले तो उडिपी नगर के श्रीकृष्ण मठ सभागार में ईद मिलन समारोह में हिंदू धार्मिक नेताओं ने भाग लेकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया था.

इस रुझान को अधिक बल प्रदान करने के लिए तमिलनाडु में तंजावुर जिले के धरमपुरम अधीनम (मठ) ने पिछले साल 24 धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए एक वर्ष का कोर्स शुरू किया. मठ प्रमुख श्री लाल श्री षणमुख देसिका गण संबंध परमाचार्य स्वामीगल बताते हैं, "अगले साल से हम इस विषय में पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू करने की सोच रहे हैं."

कुछ साल पहले तक मठाधीशों द्वारा हेय दृष्टि से देखी जाने वाली विधवाओं को भी अब मठों में प्रवेश मिलने लगा है. मसलन कांची मठ के परमाचार्य किसी विधवा और खासकर ब्राह्मण जाति की विधवा को दर्शन नहीं देते थे, अगर उसने सिर मुंड़ाकर सफेद साड़ी न पहन रखी हो. उडिपी में पुतिगे मठ के सुगुनेंद्र तीर्थ स्वामीजी कहते हैं, "अधिक समय नहीं गुजरा जब सिर न मुंडाने वाली विधवा को मठ में अछूत माना जाता था. वह प्रसादम ग्रहण करने के लिए बाकी लोगों के साथ पंक्ति में नहीं खड़ी हो सकती थी. लेकिन अब हालात बदल गए हैं." तंजावुर जिले में तिरुवव-दुतुरई अधीनम के प्रबंधक टी.एस. अरुमुगम भी पुष्टि करते हैं, "धरमपुरम और तिरुववदुतुरई मठों में विधवाओं और हरिजनों के लिए स्वामीजी के दर्शन करना अब बहुत सहज हो गया है."

हिंदू मठाधीशों की नई सक्रियता की सबसे महत्वपूर्ण वजह दरअसल यह भ्रम दूर करना है कि सामाजिक कार्य दूसरे धर्मों के लोग ही करते हैं

धर्मगुरुओं का अपना जीवन भी इन बदलावों से अछूता नहीं रहा. कांचीमठ के 95 वर्षीय सेवानिवृत्त धर्मगुरु स्वामी चंद्रशेखर सरस्वती का जमाना अब बीत गया. उनका जीवन ध्येय पैदल चलकर हिंदू धर्म और वेदों का संदेश देश में फैलाना था.

इसके विपरीत स्वामी जयेंद्र सरस्वती पिछले महीने विश्व हिंदू सम्मेलन में भाग लेने विमान से काठमांडू गए. पहले विमान तो दूर, परमाचार्य द्वारा एअर कंडीशन का सुख भोगने की भी कल्पना नहीं की जा सकती थी. उसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए उडिपी में एक समय से रूढ़िवादी माने जाने वाले मठों के तीन स्वामीजी भी विमान से नेपाल गए थे. पुतिगे मठ के सुगुनेंद्र तीर्थ स्वामीजी कहते हैं, "पुराने जमाने में उडिपी के स्वामीजी पैदल घूमकर ही हिंदू धर्म का प्रचार किया करते थे. आज तो उडिपी के स्वामियों की विमान यात्रा आम बात हो गई है.

दरअसल उडिपी पेंजावर मठ से हटाए गए पूर्व कनिष्ठ प्रमुख, 20 वर्षीय विश्व विजय तीर्थ स्वामीजी जब पिछले साल अमेरिका के छह महीने के दौरे से लौटे तो उडिपी के किसी वरिष्ठ स्वामी ने उनकी विदेश यात्रा पर आपत्ति नहीं उठाई थी. यह किसी रूढ़िवादी मठ के स्वामी की पहली विदेश यात्रा थी. वरिष्ठ स्वामियों ने सिर्फ यह आपत्ति उठाई कि यात्रा के दौरान विश्वविजय ने कुछ कर्मकांडों का पालन नहीं किया था. सुगुनेंद्र तीर्थ स्वामी कहते हैं, "विदेश यात्रा पर आपत्ति अब धीरे-धीरे कम होने लगी है." एनफील्ड के प्रबंध निदेशक और अरसे से शृंगेरी मठ के अनुयायी चले आ रहे 53 वर्षीय एन. स्वामीनाथन कहते हैं, "दर्शन तो नहीं बदला है. केवल नियमों और अनुष्ठानों में आज की स्थितियों के अनुरूप परिवर्तन किए गए हैं."

अधिकांश हिंदू मठों ने शिक्षण संस्थाएं भी शुरू की हैं. कर्नाटक शृंगेरी मठ ने हाल ही में बंगलूर में एक स्कूल खोला है जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण बोर्ड से संबद्ध है. उडिपी अडमार मठ अपने के तत्वावधान में हाल ही में शुरू किए गए अंग्रेजी माध्यम के शिक्षा संस्थान में नर्सरी से लेकर डिग्री स्तर तक की शिक्षा दी जाती है. पिछले दो दशकों में लिंगायत मठों ने अनेक ऐसे स्कूल और कॉलेज खोले हैं जिनमें व्यावसायिक और दूसरी शिक्षा दी जाती है.

हिंदू धर्मगुरु इन मठों द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्य के कई कारण बताते हैं. उडिपी अडमार मठ के विभुदेश तीर्थ स्वामीजी कहते हैं, "हम शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यतः इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि साक्षरता लोकतंत्र की सफलता की पहली शर्त है." स्वामी जयेंद्र सरस्वती बताते हैं, "सामाजिक कार्य हाथ में लेने का हमारा उद्देश्य लोगों की सच्ची सेवा करना है. दूसरा उद्देश्य मानवतावाद का प्रचार करना है जबकि तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण यह भ्रम दूर करना है कि सामाजिक कार्य दूसरे धर्म ही करते हैं."

संक्षेप में, हिंदू मठों की धार्मिक संस्कृति बदल रही है. उनका नया नारा है—गतिशीलता, नई संस्कृति, और समाज सेवा.

—एस.एच. वेंकटरा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हानी संग्रह

व्यवस्था विरोध के स्वर

मौजूदा व्यवस्थाओं की मान्यताओं को रद्द करती कहानियां

वस्था विरोधी कहानियां
ानी संग्रह
नरेंद्र मोहन, बदीउज्जमां
त प्रकाशन, दिल्ली-6
पृष्ठ: 219, कीमत: 60 रु.

व्यवस्था विरोधी स्वर पिछले 20-25 वर्षों के साहित्य का मुख्य अथवा केंद्रीय स्वर रहा है, यह कहना शायद अतिशयोक्ति हो और बहस का मुद्दा भी. पर मौजूदा राजनैतिक, आर्थिक, कृतिक व्यवस्थाओं की मान्यताओं को करने की दिशा में प्रस्तुत संकलन ही अपनी तरह का एक योगदान है. नरेंद्र मोहन और बदीउज्ज़मां के दन में संग्रहीत 24 कहानियों के पात्र अपने स्तर पर अन्याय के खिलाफ लड़ाई अंतर्मन के द्वंद्व का प्रतीक कर भी उभरी है. कुलदीप बग्गा गृहयुद्ध' और देवेंद्र इस्सर की रूर' कहानियां इसी कोटि में हैं. डर और आदर्श का द्ध' जब शहर-शहर, गांव-गांव रहा है तो लेखक सवाल ा है कि आखिर 'यह स्थिति तक रहेगी?' उधर 'मफरूर' से दूसरा सवाल जन्म लेता ा है कि व्यवस्था में रहकर भी था का विरोध कैसे करें? पर इन के जवाब देगा कौन? लेखकों को पाठकों से ही यह कसरत पूरी करने पेक्षा है.

हानियों का धरातल भी भिन्न-भिन्न ीं ग्रामीण संदर्भ में जमींदारों के जोर- के तहत पिसते भूमिहीन किसानों का भरा है तो कहीं शहरों में दफ्तरों की ा जिंदगी और ऊपर से अफसरों की के प्रति असंतोष छलकता प्रतीत है. मधुकर सिंह की 'हरिजन सेवक' न हरिजनों के संघर्ष की दास्तान का ही एक टुकड़ा है. विडंबना यह है कि ज्यादा मजूरी लेने के सवाल पर ज्यों ही उन लोगों में थोड़ी-सी आर्थिक चेतना जागृत होती है, राजनैतिक व्यवस्था भी जमींदारों की हां में हां मिलाकर उन्हें नक्सलपंथी विद्रोही करार देने को तत्पर हो उठती है. गांधीवाद की आड़ में हरिजन सेवकाई का मुखौटा ओढ़े मास्साब को भी लेखक ने खूब बेनकाब किया है.

उधर माहेश्वर की 'शुरुआत' में ऐसे ग्रामीण युवा की पीड़ा उभरी है जो रोजगार की उम्मीद में शहर चला आता है. पर पुलिस का अत्याचार उसे व्यवस्था विरोधी गुप्त दल का पता लगाकर उसमें शामिल होने को प्रेरित करता है. इसी तरह जगदीश चतुर्वेदी की 'दमन का चक्कर' में मांगी और सोमा उन लाखों भूमिहीनों का प्रतीक बनकर उभरे हैं जो जमींदार के जुल्मों के कारण अपनी मिट्टी से जुदा होकर भाग्य आजमाने शहर चले आते हैं पर वहां भी मिस्टर अली सरीखे पूंजीपति और उनकी व्यवस्था उन्हें जीने नहीं देती.

> **"असली भेड़िये पकड़ लो तो नकली भेड़िये खुद-ब-खुद गिरफ्त में आ जाएंगे. लेकिन प्यारे, इतना मजबूत जाल फैला है इन भेड़ियों का कि इन्हें पकड़ना आसान नहीं. देश के ज़र्रे-ज़र्रे को जकड़े हुए हैं"**
> **'दीमक' से**

परोक्ष रूप से हरित क्रांति को मुंह चिढ़ाती ये कहानियां हमारे देहाती जीवन के विरोधाभासों को ही उजागर करती हैं. उधर शहरों में दफ्तरों के दमघोंटू माहौल का चित्रण भी कुछ कहानियों में है. रवींद्र कालिया की 'काला रजिस्टर' में दफ्तर के प्रायः सभी लोगों में बॉस के प्रति विरोध तो उपजता है पर उसे सामने लाने में वे असमर्थ हैं. भेंगा नामक एक पात्र यह प्रयत्न करता है लेकिन उसका विरोध भी संगठित न होकर छोटे अफसरों के टेलीफोन तार काट देने, अपने सीनियर की कुर्सी की बेंत काट देने और बाथरूम का आदमकद आईना फोड़ देने तक सीमित है.

इसी तरह धर्मेंद्र गुप्त की 'अपंग संज्ञा' एक बुद्धिजीवी की दफ्तरी जिंदगी का पन्ना है जिसमें गुजरने के दौरान उसका परिचय कुछ सामाजिक हकीकतों से होता है. लेकिन 'व्यवस्था विरोध' की लड़ाई में आखिर वह भी यूनियनबाज़ी के उस रंग में रंग जाता है जहां झूठा केस करना भी सही मान लिया गया है. उसकी जिंदगी शायद ऐसे ही मूल्य स्थापित करने में निकल जाती है.

व्यवस्था के विरोधाभासों का कैसे इस्तेमाल किया जाए, इस बारे में व्यवस्था विरोधियों के भिन्न-भिन्न तर्क हो सकते हैं. पर 'सलीब' में विष्णु प्रभाकर ने बड़ी खूबी से एक भ्रष्ट अफसर को एहसास दिलाया है कि वह गलत रास्ते पर जा रहा है. लेकिन हैरानगी है कि सस्पेंड किए जाने के बाद भी उसे बहाल कर दिया जाता है.

संग्रह की कुछ कहानियों से जहां पाठक के मन में आशा का संचार होता है, वहीं कुछ ऐसी भी हैं जो उसे निराशा के गर्त में धकेल सकती हैं. इनमें अशोक अग्रवाल की 'व से वजीर' और खुद संपादक दिवंगत बदीउज्ज़मां की 'पुल टूटते हुए' शामिल हैं.

पर राजी सेठ की 'अंतहीन' कहानी भ्रष्टाचार के बारे में सवाल उठाती है कि असली अभियुक्त कौन है, इसका फैसला कौन कर सकता है? यानी पन्ने पलटते जाइए, हर कहानी के अंत में सवाल दर सवाल खड़े होते जाते हैं. इनका जवाब भी शायद लेखकों के दायरे में नहीं है. तभी तो व्यवस्था के बारे में अपनी आम परिभाषा देते हुए संपादकगण उसकी विशेष परिभाषा से कन्नी काट गए हैं.

संकलन की दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके लेखकों ने अपनी रचनाओं का पारिश्रमिक भारतीय लेखक संगठन के 'लेखक सहयोग निधि' को सौंप दिया है. ये कहानियां व्यावसायिक दृष्टि से नहीं लिखी गईं. सचमुच यह प्रयास सराहनीय है.

संपादकों का दावा है कि लेखक के पास "अपने विचारों और स्वप्नों को कला और कल्पना की ताकत से संयोजित करके व्यवस्था को चुनौती देने के सिवा अन्य कोई विकल्प नहीं है" पर विडंबना यह है कि देश भर में लेखक 'प्रगतिशील', 'व्यवस्था विरोधी', 'क्रांतिकारी' आदि खेमों में बंटे हुए हैं और व्यवस्था विरोध के नाम पर भी एकजुट नहीं हो पाते. —ओमप्रकाश सराफ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कहानी संग्रह

दानवी दौर की दास्तान

साझा संवेदनाओं और मानवीय मूल्यों के जतन का चित्रण भी

काला नवंबर
कहानी संग्रह
संपादक—**सुरेंद्र तिवारी**
अभिव्यंजना, नई दिल्ली-110026
कुल पृष्ठ-296, कीमत 100 रु.

इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 31 अक्तूबर से 3 नवंबर 1984 तक दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में जो कुछ हुआ वह क्या मुल्क के बंटवारे के वक्त हुए हादसों या आजादी के बाद मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ़, भिवंडी या अहमदाबाद में बार-बार हुई घटनाओं की पुनरावृत्ति जैसा ही था? '84 की उन भयावह घटनाओं को क्या इस देश के लिए चिर-परिचित 'दंगे' की संज्ञा दी जा सकती है? उन खौफनाक चार दिनों के चश्मदीद जानते हैं कि अगर वह दंगा था तो एकतरफा था क्योंकि दूसरा पक्ष आक्रमण की तो छोड़िए, अपना बचाव भी ठीक से नहीं कर पाया. और दंगा जब एकतरफा होता है तो वह फिर दंगा नहीं रहता, नरसंहार हो जाता है. पर उस दानवी दौर में भी संवेदनाओं और मानवीय मूल्यों की लौ बराबर दिपदिपाती रही. ये कहानियां ही नहीं बल्कि उपलब्ध तथ्य भी इसके गवाह हैं.

दिल्ली की हिंसक वारदातों के तुरंत बाद मानवाधिकारों के लिए लड़ने वाली एक संस्था ने राजधानी की 19 प्रभावित बस्तियों में सर्वेक्षण कराया था. उसके मुताबिक 72 फीसदी लोगों को वारदातों की खबर इस रूप में मिली कि शहर भर में सिखों पर हमले हो रहे हैं; इनमें से 58 फीसदी ने खबर मिलते ही अपने सिख मित्रों और पड़ोसियों से संपर्क साधने की कोशिश की; 59 फीसदी ने पीड़ित पड़ोसियों को बचाने की विभिन्न तरीकों से कोशिश की और नतीजे में गालियां, धमकियां और कहीं-कहीं लाठियां भी खाईं; 34 फीसदी ने पीड़ितों को अपने घर में छिपा लिया; 28 फीसदी ने उन्हें खाना, दवाइयां, कपड़े वगैरह मुहैया कराए; 12 फीसदी उनकी खैरखबर लेने राहत शिविरों में भी गए और अमन कमेटियां बनाईं; 12 फीसदी लोगों ने हिंसा की इत्तला बाकायदा पुलिस को दी और सबसे बड़ी बात यह कि जिन 68 फीसदी पीड़ितों से सर्वेक्षणकर्ताओं ने मुलाकात की उन्होंने कहा कि उनके पड़ोसी ही उनकी रक्षा के लिए आगे आए.

साझा संवेदनाओं की बानगी इस संग्रह में छपी भीष्म साहनी की कहानी 'झुटपुटा' में देखिए. दो दिन बाद दूध मिलने की आस में लंबी लाइन लगाए खड़े, आसपास हुई खूंरेज वारदातों की चर्चा में मग्न मुहल्ले के लोगों के लिए आखिरकार वही पुराना सिख ड्राइवर दूध की लॉरी चलाता बूथ पर पहुंचता है और अचंभे में पड़े प्रोफेसर कन्हैयालाल लाइन से बाहर निकलकर उससे पूछते हैं, "सरदार जी, आप कैसे...?" इस पर सिख ड्राइवर मुस्कराकर जवाब देता है, "बीबा बच्चों ने दूध तो पीना है ना! मैंने कहा, चल मना, देखा जाएगा जो होगा, दूध तो पहुंचा आएं."

> **"भले लोगों की आत्माएं नहीं भटकतीं बदला लेने के लिए. पर मान लो अगर कभी मरे हुए लोग बोल ही उठें? वे लोग जो निहत्थे थे, निर्दोष थे और मासूम भी, तब वे क्या कहेंगे?"**
>
> इसी संग्रह से

वैसे इस संग्रह में संकलित 27 कहानियों में से ज्यादातर का स्वर यही है. इनमें से तीन कहानियां '84 के 'काले नवंबर' की दास्तान नहीं हैं, उनमें हिंदू-मुसलमानों के सदाबहार दंगों को आधार बनाया गया है. बाकी कहानियों में से तकरीबन आधी जहां विष्णु प्रभाकर, भीष्म साहनी, महीप सिंह, हृदयेश, दीवान वीरेंद्रनाथ, गिरिराज किशोर, बीर राजा, यादवेंद्र शर्मा 'चंद्र' मृदुला गर्ग जैसे स्थापित कथाकारों की कलम से निकली हैं वहीं बाकी नए, लेकिन चर्चित हस्ताक्षर हैं.

स्थापित लेखकों की रचनाएं अत्यं मार्मिक हैं. उनमें उन कारणों का भ खुलासा है या फिर उन पर सवाल हैं, जिनसे ऐसे हालात बनते हैं. जैसे दीवान वीरेंद्रनाथ की 'भाबो भांगावाली' में, "आवाजें इतनी खौफनाक थीं कि लोगों ने बोलना तो क्य सोचना भी बंद कर दिया था—डर था कि कहीं सोच से आवाजें और ज्यादा खफा हो जाएं—खौफ था कि आवाजों को समझ और पहचानने की कोशिश जिंदगी से हा धोने का बहाना न बन जाएं...इसी खौफ दिल छोटे और आंखें बड़ी होती गईं.... पंजाब की स्थितियों का इससे सटीक वर्ण शायद ही कहीं हो सकता है. गिरिराज किशोर की कहानी 'फिर स्टेशन आ रहा है' में '84 के उस वहशीपन पर एक पीड़ित की प्रतिक्रिया, "मुल्क तो सबका है न.... सा का सारा अपने मुंह में ही रख लो. अ दूसरों का भी हक है." और फिर व्यवस्थ पर तीखी टिप्पणी, "....इस साले जनतंत्र ही तो इस मुल्क की मां...." मृदुला गर्ग 'अगली सुबह' में उस माहौल पर एक गंभी सवाल, "कहां से आते हैं वे लोग, दंगा हत्यारे? कल तक सब अपने काम-धंधे लगे थे, किसी का किसी से कुछ लेना-देन नहीं था, फिर आज कैसे एक-दूस को पहचान गए वे, कैसे मारने ल लोगों को गुट बनाकर? कौन हो हैं ये लोग, कहां से आते हैं अ फिर कहां जाकर छिप जाते हैं पंकज बिष्ट ने 'मोहेंजोदड़ो' में अह सवाल उठाया है, "मरे आदमी न बोलते. भले लोगों की आत्माएं न भटकतीं बदला लेने के लिए. मान लो अगर कभी मरे हुए लो बोल ही उठें? वे लोग जो निह थे और निर्दोष थे और मासूम भ तब वे क्या कहेंगे?"

बहरहाल, यह प्रयास प्रशंसनीय है. जै कि इसके संपादक सुरेंद्र तिवारी कहते "इस संग्रह की उपयोगिता इतनी ही है हम उन चेहरों की पहचान करें जो आदमी से पशु बनाते हैं?" लेकिन वे चेह क्या हमारे अपने ही नहीं हैं? दरअसल ऐ कथाओं की उपयोगिता अंतर्मन में झांक सामयिक परिस्थितियों का विश्लेषण क और खुद को अमानवीयता के खिलाफ के लिए तैयार करने में ज्यादा है.

—जगदीश उप

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

माथे पर सिंदूर की लाली
आंचल में आभा रेशमी
कंगन में चमक सुनहरी.
हाथों में रचाए मेंहदी.
इन्हीं रंगों में रंग कर.
रंगोली से किया दीवारों ने श्रृंगार.
नव-वधू के स्वागत में
लिए इंद्रधनुषी मुस्कान.

नया रंगोली
ऐक्रिलिक इमल्शन
रंगो की बहार. दीवारों का श्रृंगार

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सटीकता...
सुंदरता के आवरण में

श्रेष्ठता
अंदर

श्रेष्ठता
बाहर

ऑल्विन
क्वार्ट्ज़

भारत की सबसे ज़्यादा बिकनेवाली
क्वार्ट्ज़ घड़ियाँ

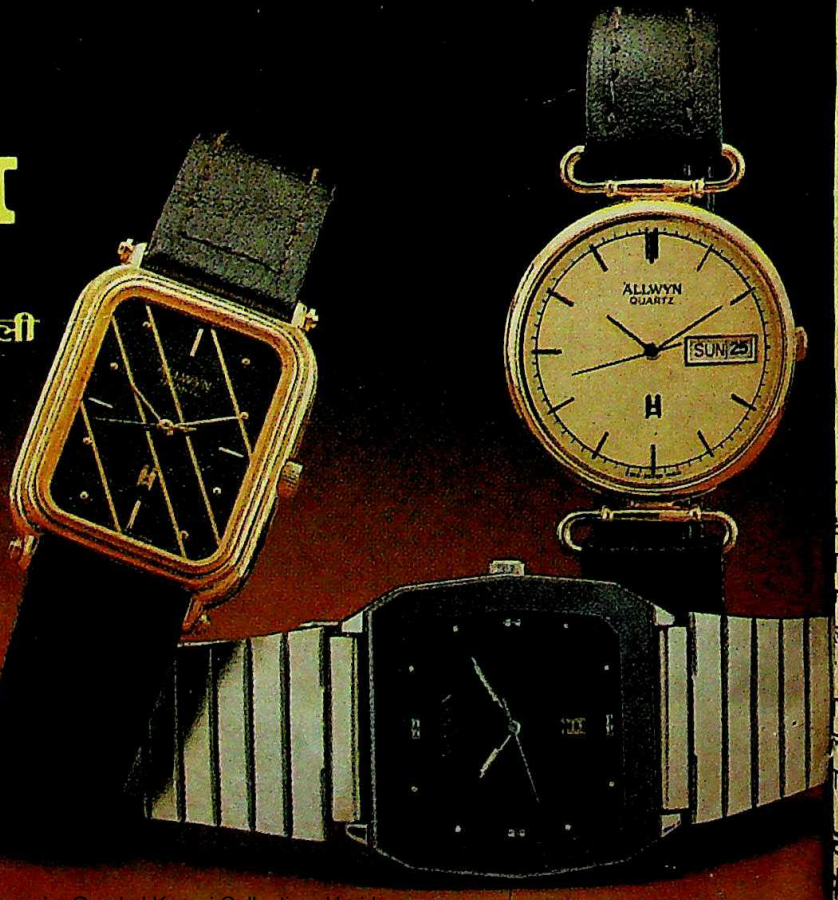

Time
FOR THE NEW GENERATION
ALLWYN

Manufactured under licence from
SEIKO

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सही निर्णय का

अन्दरूनी राज़

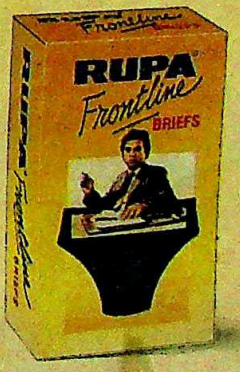

जब त्वचा की सुरक्षा का है, तो
धानी बरतने में ही समझदारी है।
निर्णय आपके लिये परेशानी का
ा बन सकता है। इसलिये रूपा
लाइन ही खरीदिये और निश्चित
। भारतीय जलवायु के उपयुक्त,
तम तकनीक से बना रूपा
लाइनें आपकी त्वचा को बराबर
देता है।

शतप्रतिशत सुती धागे से बना। इसकी उत्कृष्ट फिनिश रेशम सी कोमलता का अहसास दिलाये। फिटिंग पूर्णतः आरामदायक। इम्पोर्टेड रबर से बना इलास्टिक। निराले रंगो में उपलब्ध। इन्हीं सब खूबियों के कारण रूपा फ्रन्टलाइन सही निर्णय लेने में आपका सहायक होता है।

RUPA®

Frontline

BRIEFS

ट ओपन' की स्पेशल सुविधा
के रूपा फ्रन्टलाइन ब्रीफ़ में

होसियारी, कलकत्ता ७०० ००७ का एक उत्कृष्ट उत्पादन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

भारत में पहली बार, अपनी किस्म का खास

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कल्याण चक्रवर्ती

चौधरी: जीत की तैयारी

◆ वह एक यादगार महफिल थी, सिर्फ श्रोताओं के लिए ही नहीं बल्कि मलिका-ए-गज़ल के लिए भी. बंटवारे के बाद पहली बार भारत आई **फरीदा खानम** के जेहन में खूबसूरत अतीत की याद आज भी ताजा है, "वह अमृतसर जहां मैं बड़ी हुई, और यहां तक कि वहां खाई हरेक छोटी-से-छोटी मिठाई की याद हमेशा मेरे साथ रहती है." उनके संगीत की जड़ें पटियाला घराने में हैं. पिछले पखवाडे हुई दो महफिलों में उन्होंने अपनी जिंदादिली और दिल को छू लेने वाली गायकी से दिल्ली के लोगों पर मानो जादू ही कर दिया. खयाल, हल्की-फुल्की गज़लें और सोंधी महक के पंजाबी लोक गीत गाते समय उनका रसीला सुर खूबसूरती की बुलंदियों पर पहुंच गया. और तब उन्होंने अपनी मशहूर गज़ल—'आज जाने की जिद न करो' गाई. लोग झूम उठे और सुर में सुर मिलाने लगे. वे कहती हैं, "मुझे लगता है कि यहां लोग पाकिस्तान से आने वाले कलाकारों की बहुत इज्जत करते हैं और प्यार देते हैं."

खानम: सुर की बुलंदियां

◆ वे पुरानी कारों के शौकीन हैं. तीन बार पुरानी कारों की राष्ट्रीय रैली के विजेता रह चुके 45 वर्षीय **सलाउद्दीन 'सैलो' चौधरी** कहते हैं, "जो खेल की तरह शुरू हुआ था अब वह जुनून और जिंदगी का एकमात्र मकसद बन गया." 1961 तक वे कारों की रैली में शामिल होते थे, पर फिर पुरानी कारें इकट्ठा करने और उनकी रैली में भाग लेने का शौक पाल लिया. अब चौधरी अपनी बीवी और साथी ड्राइ-वर नीना के साथ ग्रेट अमेरिकन रेस में अपनी 1987 की जीत को दोहराने जा रहे हैं. 22 जून से शुरू होने वाली इस रैली को, जिसमें 1937 से पहले के मॉडल की कार ही ली जा सकती है, लास एंजिलिस से बोस्टन तक 4,000 मील का रास्ता तय करना होगा. रैली में किसी भी आधुनिक उपकरण के इस्तेमाल की इजाजत नही है. चौधरी मानते हैं कि यही उनके लिए फायदे की बात है. इस रैली में 1928 की कस्टम में बनी कैडिलेक ला सैले कार चलाएंगे.

◆ उनके रचनात्मक निर्माण ने उनके लिए पुरस्कारों का ढेर लगा दिया है. अहमदाबाद के वास्तु-शिल्पी, शिक्षाविद् और नगर नियोजक 60 वर्षीय **बालकृष्ण वी. दोषी** अपने प्रभावशाली डिजाइनों और मौलिक शहरी योजनाओं के लिए मशहूर हैं. दोषी का नाम इस महीने फिर सुर्खियों में आ गया. 17 जून को अमेरिकी इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कीटेक्चर पद्मश्री दोषी को उनकी शहरी योजना के लिए पुरस्कार देगी और 28 जून को पेरिस की 217 साल पुरानी 'अकेदमी डी आर्कीटेक्चर' से स्वर्ण पदक पाने वाले वे पहले भारतीय होंगे. दोषी कहते हैं, "अपने नाम को उन दिग्गजों की सूची में

दोषी: पुरस्कार ही पुरस्कार

भवान सिंह

देखना बहुत उत्साह देता है जिनकी आप हमेशा तारीफ करते रहे हों."

◆ जादूगरी में उसका जवाब नहीं. अपनी नटखट मुस्कान और मंजी हुई बाजीगरी से वह लोगों को सम्मोहित कर लेती है. भारतीय जादूगर समाज के सालाना जलसे में **बेबी प्रिया कोहिनूर** पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की जादूगर थी. पिछले पखवाड़े राजधानी में इस आठ साल की छोटी-सी बच्ची ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. उसने एक खाली झोला लिया, फिर

प्रिया: नन्हे हाथों का कमाल

छूमंतर! और उसमें से का गुच्छा निकाल दिया. जलता हुआ कागज डाला फाख्ता निकाल दी. पत्तों को हवा में लह उनका एक पिरामिड उसके. पिता जादू नूर कहते हैं, "म बहुत चुस्त और जाती है." वे खुद 2 इसी धंधे में हैं. महाराष स्कूल की चौथी कक्षा में प्रिया को चित्रकारी और भी इतनी ही महारत हा

सिक्का: पुरुष-प्रध से दो-दो ह

◆ भारत में क्लब के हाल त सदस्य थे—सब पुरुष. पर जब एक इंजीनियरिंग निदेशक 39 वर्ष **सिक्का** ने सुना पुरुषों की सदस इसके नियम में है, वह भी केवल अमेरि वह हरकत में आ गईं. लगा कि "यह सरासर भेद वे 15 साल से रोटरी क्ल काम कर रही हैं. बात रो के मुखिया निल राबि पहुंचाई जाती कि इससे उन्होंने क्लब की दिल्ली शाखा को राजी कर दुनिया की पहली गैर महिला रोटेरियन ब रोटरी इंटरनेशनल में भूचाल आ गया: धमकी उन्हें न निकाला गया तो की कार्रवाई होगी. अ पखवाड़े सिक्का ने इस खिलाफ उच्च न्यायालय आदेश ले लिया.

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar